Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Chennai and eGangotri

INDIA TODAY

1988
Jul-Dec

G. K. V.
Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
078 604
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

078604

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

RT-01174

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by

15 जुलाई 1988 5 रुपए

इंडिया टुडे

जड़े जमाने की जद्दोजहद

बोफोर्स

लाजवाब कर देने वाले तथ्य

वी.पी. सिंह

कांग्रेस (इ)

मुश्किलों का कहर

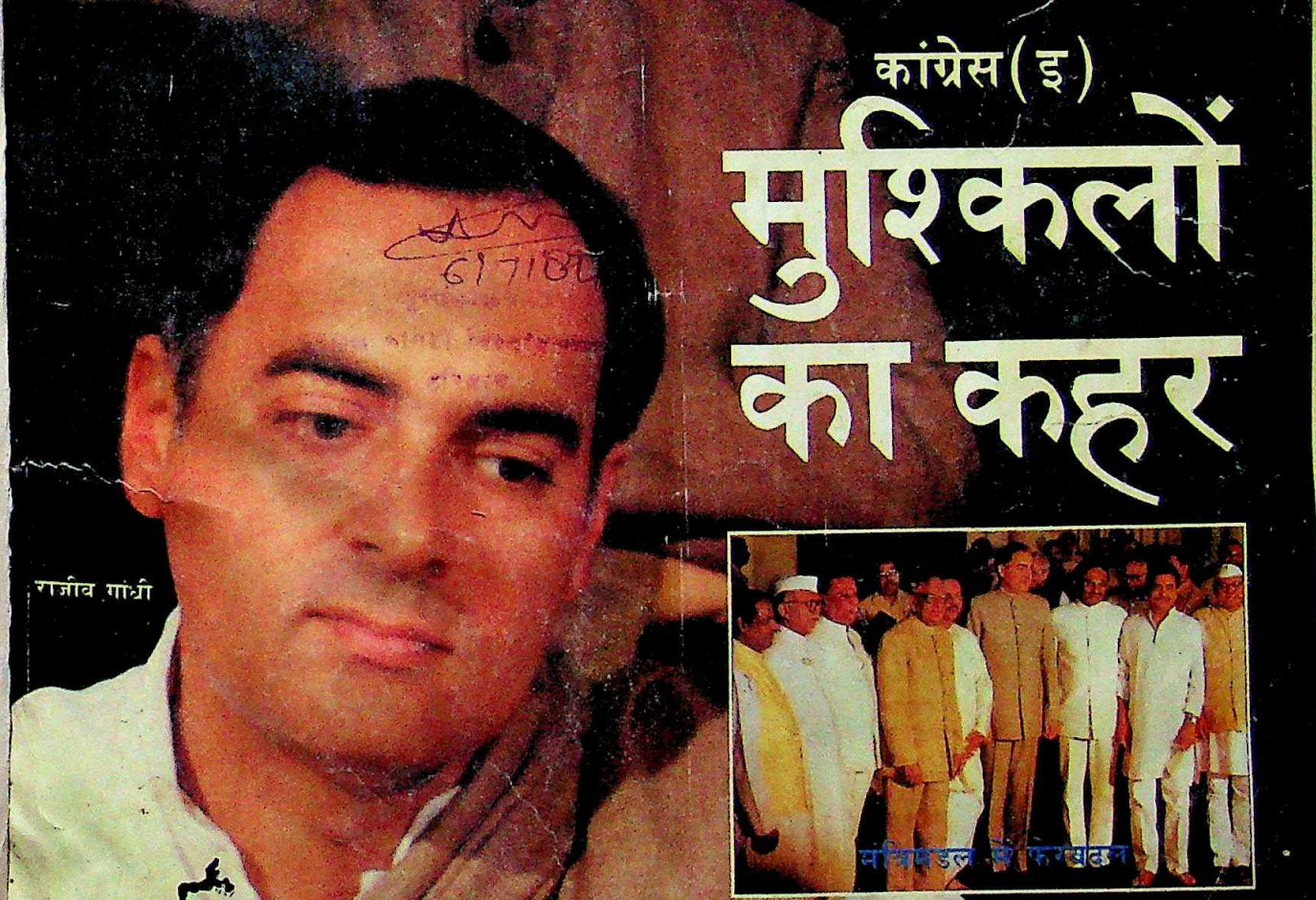

राजीव गांधी

मन्त्रिमंडल में फेरबदल

हताशापूर्ण हथकंडा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमूल चॉकलेट
प्यार की मीठी भेंट

वितरक :
गुजरात को-ऑपरेटिव
मिल्क मार्केटिंग
फेडरेशन लिमिटेड, आणंद.

छ स्वादिष्ट चॉकलेट
अमूल मिल्क चॉकलेट, अमूल क्रिस्प, अमूल कॉफ़ी,
अमूल फ्रूट एण्ड नट, अमूल बिटर, अमूल ऑरेंज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुश्किलों का कहर

उपचुनावों में मिली जबरदस्त पराजय के मद्देनजर इंका आलाकमान ने अपने पुराने नुस्खे के तहत इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल किया. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए. लेकिन ये फेरबदल क्या पार्टी की छवि सुधार पाएंगे?

आवरण कथा.....16

लाजवाब कर देने वाले तथ्य

पिछले पखवाड़े जब सरकार खुद को बोफोर्स तोप घोटाले में पाक-साफ साबित कर निश्चिंत हो चुकी थी, दैनिक 'द हिंदू' ने घोटाले से संबंधित दस्तावेज प्रकाशित करके एक और धमाका कर डाला. प्रकाशित सबूतों और सरकार की संभावित प्रतिक्रिया का आकलन.

खास रपट.....28

धमाकों से थमीं धड़कनें

पिछले महीने पंजाब के आतंकवादियों ने अमृतसर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली में भारी बम विस्फोट किए ताकि हिंदू भड़ककर बदले की कार्रवाई करें. उधर ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद गिरफ्तार आतंकवादियों के इकबालिया बयानों से कई संगीन तथ्य सामने आए.

आजकल.....32

जीवन को मिला नया मकसद

दो वर्ष पहले हुए मिजोरम समझौते ने जंगल में छिपे मिजो बागियों को जीने का नया मकसद दिया. अब वे सामान्य घरेलू जीवन की ओर लौट रहे हैं. इस प्रक्रिया में उनकी कठिनाइयों और उम्मीदों का ब्यौरा और उनके पुनर्वास में मिली कामयाबी पर रिपोर्ट.

विशेष लेख.....48

नायिका के नए तेवर

हीरो के गीतों के सुर पर सरसों के सुनहरे खेतों में नाचती हीरोइन के दिन अब लद रहे दिखते हैं. हिंदी रजतपट पर उभरती नई नायिका की छवि हठीली और अक्सर प्रतिशोध की आग में धधकती महिला की है जो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती.

सिनेमा.....80

जड़ें जमाने की जद्दोजहद

हिंदुजा बंधुओं ने अपनी संदेहास्पद छवि से उबरने की भारी जद्दोजहद शुरू कर दी है. भारतीय उद्योग में पांव जमाने और प्रतिष्ठा पाने के लिए यह घराना अब कई कंपनियों का अधिग्रहण करने और नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी में लगा हुआ है

कारोबार.....56

कसौटी.....9
तेवर.....10
राजरंग.....11
हिंदोस्तां हमारा.....12
बीता पखवाड़ा.....14
आवरण कथा
कांग्रेस (इ) : मुश्किलों का कहर.....16
खास रपट
बोफोर्स घोटाला :
लाजवाब कर देने वाले तथ्य.....28
आजकल
पंजाब : धमाकों से थमीं धड़कनें.....32
गिरफ्तार आतंकवादी :
संगीन सूचनाओं के स्रोत.....35
कर्नाटक : एक और पराजय.....37
केरल : अपने भी नाराज.....39
लद्दाख : बर्फ की गरमी और तल्खी.....40
कश्मीर : घाटी में असंतोष.....42
आंध्र प्रदेश : जान आफत में.....43
बिहार : जघन्य हत्याकांड.....44
आखिरी बात.....46
विशेष लेख
मिजो बागी : जीवन को मिला मकसद.....48
राज्य-दर्पण.....51
व्यापार-चक्र.....54
कारोबार
हिंदुजा बंधु : जड़ें जमाने की जद्दोजहद.....56
शेयर बाजार : नया जोश, नई तेजी.....58
किर्लोस्कर : उबरने की अनूठी मिसाल.....62
शेयर बाजार.....66
वाणिज्य-वार्ता.....67
विज्ञान
एएसएलवी : अंतरिक्ष आरोहण को तैयार...68
विज्ञान चर्चा.....70
प्रतिरक्षा
वायुसेना : एक और अप्रिय मिसाल.....71
नौसेना : कैप्टन पर संदेह.....74
खबरवालों की खैर.....76
बरताव
पंजाब : सहमे नौनिहाल.....77
टीवी
नाटक : सुधार के लिए अंततः चेते.....78
सिनेमा
हिंदी फिल्में : नायिका के नए तेवर.....80
किताबें.....83
जगबीती.....86
राजीव की विदेश यात्रा :
कुछ लेकर आए, कुछ देकर.....88
खेलकूद
पी.टी. उषा : परों को तोलती उड़नपरी....92
स्वास्थ्य
कलकत्ता : जिहादी पर जुल्म.....95
विकास
गुजरात : सहानुभूति के सरोवर.....96
रहन-सहन
मलेरकोटला : जिसे रोशन खुदा करे.....98
टीवी
'रामायण' : राम नाम की लूट है.....102
चर्चित चेहरे.....104

आवरण : रघु राय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जांबाज़, कामयाब मर्दों के लिए

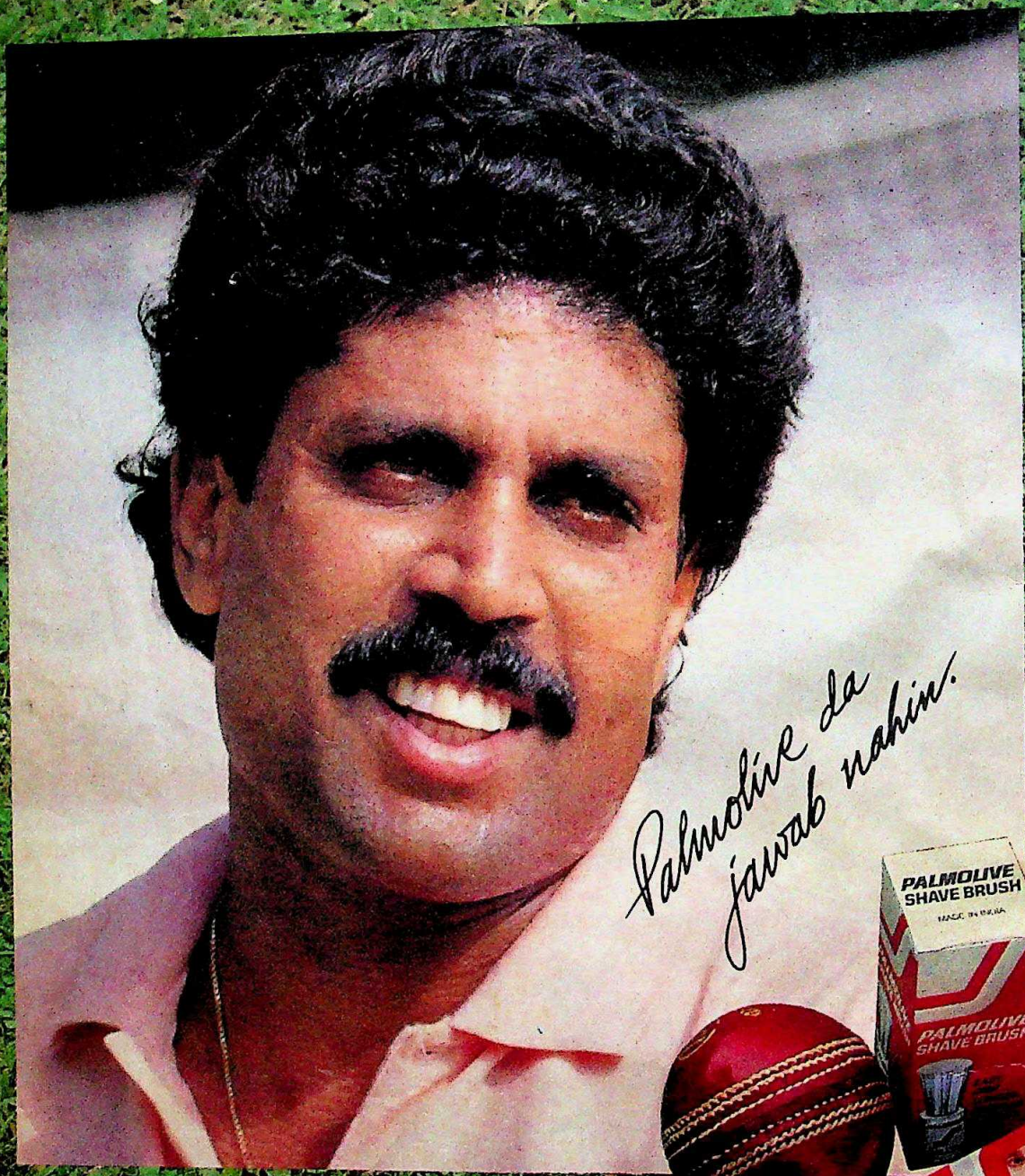

पामोलिव
शेव क्रीम और ब्रश

एस जी एल-4 युक्त

पामोलिव शेव क्रीम–डीलक्स लादर, लेमन फ्रेश और मेंथॉल कूल में उपलब्ध.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऑल्विन प्रतीक्षा करने लायक क्यों है?

078604

ऑ **ल्विन की अपनी अलग श्रेणी है**
किसी भी समय, ऑल्विन के लिए प्रतीक्षा सूची होती है। और ऐसे लोग भी, जो अपना ऑल्विन प्राप्त करने के लिए खुशी से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि ऑल्विन रेफ्रिजरेटर की अपनी अलग श्रेणी है। यह सविशेष शांत निष्पादक अतुलनीय लक्षणों के साथ, वर्षों तक बिना तकलीफ सेवा देने के लिए बना है। आप खुद जाँच करके देख लें।

हि **ताची निर्मित कॉम्प्रेसर**
शांत, अस्खलित और बिना तकलीफ कार्यक्षमता के लिए।

वो **ल्टेज स्टेबिलाइसर की आवश्यकता नहीं**
क्योंकि वह १७० से २५० वोल्ट तक बिजली के उतार चढ़ाव को अपने में समा लेने के लिए बना है।

रो **ल बॉन्ड फीज़र**
शीघ्र गति से बनते बर्फ, ताजी सब्जियों और फलों के लिए।

स **ल्फ ड्रेइनिंग सिस्टम**
बटन दबाने मात्र से स्वच्छ और शीघ्र डिफ्रॉस्टिंग के लिए।

अ **धिक वस्तुओं का समावेश करता है**
सब रेफ्रिजरेटरों की तुलना में ऑल्विन में क्रिस्पेटर। शीतक ट्रे का सर्वाधिक परिमाण है।

इ **कहरा, ऊँचा और परिष्कृत**
अन्यों की तुलना में फर्श पर कम जगह लेता है।

वि **शाल श्रेणी**
ऑल्विन १६५ और ३०० लिटर के दो दरवाजोंवाले और एक दरवाजेवाले मोडेल में, आकर्षक रंगों के चयन के साथ आता है।

७ **वर्षों की विश्वस्त गॅरंटी**
वर्षों तक बिना तकलीफ सेवा के लिए।

दे **शभर में सेवा हेतु विशाल नेटवर्क**
एक फोन कॉल पर अविलंब सेवा के लिए।

ऑ **ल्विन का अनोखा संरक्षण करार प्राप्त करें.**

IS 1476
ISI
एक दरवाजेवाले सभी ऑल्विन रेफ्रिजरेटरों पर आइ एस आई चिह्न होता है।

ALLWYN

* अधिक विवरण के लिए अपने नजदीकी ऑल्विन क्षेत्र कार्यालय का संपर्क करें।

ऑल्विन सदा के लिए है।

हैदराबाद ऑल्विन के क्षेत्र कार्यालय : अहमदाबाद फोन: ४६३१८१, बनगलौर फोन: २३८८८५, भोपाल फोन: ६४१२२, भुवनेश्वर फोन: ५२२७१, बंबई फोन ४९२७५७५, ४९२७५८६, ४९३४१७८, ४९२१०५१ कलकत्ता फोन: ४४०४३७, ४४६८५३, ४३३५७६. चंडीगढ फोन: ४१९४१, कडप्पा फोन:२२३०, एर्नाकलम फोन:३६८००२, गौहटी फोन: ३२६९१, गाजियाबाद फोन: ८४३२०४, हैदराबाद फोन: ४३४०७, जबलपुर फोन: २२६६५, जयपुर फोन: ६५७२०, कानपुर फोन: ४१४१०, लखनौ फोन: ३२१२१, मदुरै फोन: ३२१२५, नई दिल्ली फोन: ७३४७४०, ७३०७१५, पटना फोन: ३२७४५, पुना फोन: ३९०२९, विजयवाडा फोन: ६२५४४, विशाखापट्टणम फोन: ६१६५२.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

MAA COMMUNICATIONS/HAL/A/HIN/88

आरामदेह जेनरेटर

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

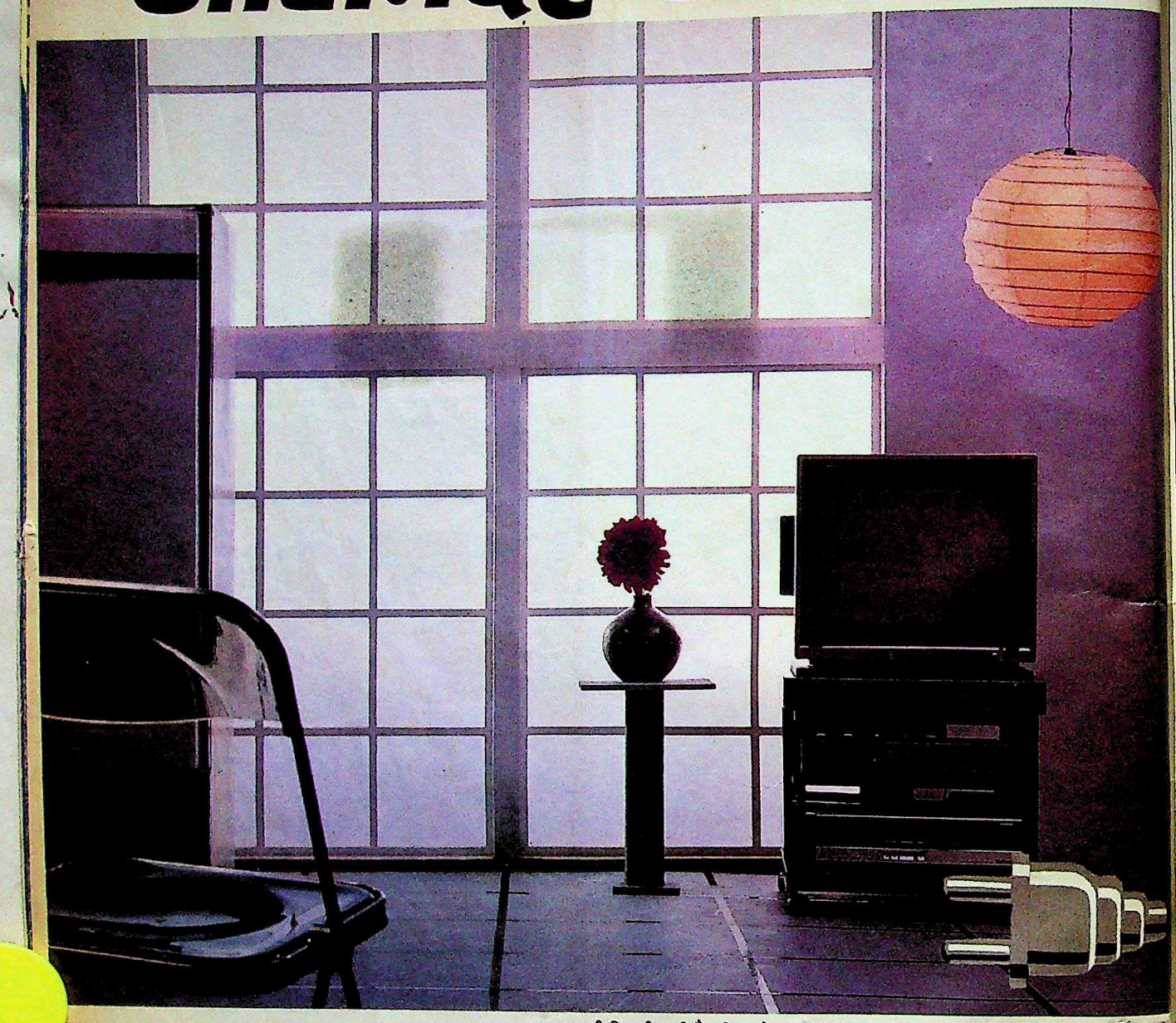

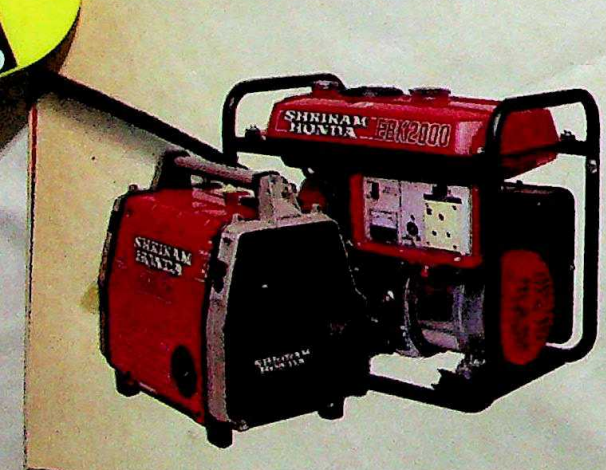

जब भी बिजली जाती है, श्रीराम होन्डा की शक्ति आपको सारी परेशानियों से बचाती है। बत्तियाँ, पंखे, फ्रिज़ और रसोई के दूसरे उपकरण काम कर सकते हैं। टेलीविजन आपका मनोरंजन कर सकता है। आप पूरी सुविधाओं के साथ घर में रह सकते हैं।

होन्डा—दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक पोर्टेबल जेनसेट्स के निर्माता—की ताकत अब आपकी ताकत है। होन्डा जेनसेट्स भारत के लिए नए नहीं हैं— १००,००० से भी ज्यादा होन्डा जेनसेट्स आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विदेश से आयात किए गए हर पाँच में से चार जेनसेट्स 'होन्डा' ही हैं।

अब श्रीराम और होन्डा का संयुक्त सहयोग आपके लिए होन्डा के दो भारत में प्रमाणित मॉडल्स लाया है। हर मॉडल ईंधन की बचत करने वाला, बिना आवाज़ काम करने वाला, हल्का, भरोसेमंद, और सुरक्षित है। श्रीराम होन्डा का हर जेनसेट स्थिर वोल्टेज देता है। श्रीराम होन्डा के हर जेनसेट के पीछे है होन्डा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्यातिप्राप्त सर्विस।

अधिक जानकारी और मुफ्त प्रदर्शन के लिए संपर्क करें—श्रीराम होन्डा के ८० से भी अधिक डीलर्स में से-किसी एक से।

श्रीराम होन्डा पॉवर इक्विपमेन्ट लिमिटेड
[illegible], ९ राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-११०००८
फोनः ५७३९९०३/५७२३५२८.

SHRIRAM HONDA
PORTABLE GENSETS

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष 2, अंक 17 1-15 जुलाई, 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद , हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN. तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली ; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास ; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर ; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

विश्वास की मुहर

आवरण कथा 'राजा की अग्निपरीक्षा' (30 जून) पढ़ी. इलाहाबाद लोकसभा उप-चुनाव जनमोर्चा नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए अग्निपरीक्षा से भी बढ़कर था. लेकिन राजा साहब ने यह चुनाव एक लाख ग्यारह हजार मतों से जीतकर सिद्ध कर दिया है कि जनता केवल सच्चे नेता को ही अपना समर्थन देती है.

—अजय मल्होत्रा, नई दिल्ली

■ यह सोचना गलत है कि इलाहाबाद की जनता ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट दिया. बल्कि जनता ने तो उस आंदोलन पर अपने विश्वास की मुहर लगाई है जो विश्वनाथ प्रताप सिंह का पर्याय बन गया है. भारत की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन का यह शुभ संकेत है.

—अ.कु. श्रीवास्तव, लखनऊ (उ.प्र.)

■ वी.पी. सिंह को जिताकर इलाहाबाद की जनता ने कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों को खुलेआम नकारा है. इस पर इंकाइयों का यह कहते फिरना कि जनता का कांग्रेस में पूरा विश्वास है, ढिठाई नहीं तो क्या है?

—संजय श्रीवास्तव, इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ इस उपचुनाव में 'रामायण' के 'राम' अरुण गोविल द्वारा चुनाव प्रचार करवा कर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि दूरदर्शन, फिल्म आदि सत्ता पक्ष की मानो जायदाद हों जिसे वह जब चाहे मनमर्जी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. गोविल की छवि जितनी 'रामायण' में राम के अभिनय से सुधरी थी उतनी ही चुनाव प्रचार करने से धूमिल हुई है.

—रमाशंकर वाजपेयी, राबरेली (उ.प्र.)

अबाध सिलसिला

आजकल के अंतर्गत 'चौथे खंभे को जमीन' (30 जून) में कुछेक अखबारों द्वारा जमीन-हड़पो अभियान पर आपकी रिपोर्ट पढ़ी. इससे पहले भी रायपुर से प्रकाशित 'अमृत संदेश' के बारे में लिखा गया था. लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. आप चाहे जो लिखें, अखबारों के नाम से खाने का सिलसिला जारी ही रहेगा.

—मनोज कुमार, भोपाल (म.प्र.)

खुसरो से सबक

'समन्वयवाद का सबक' (30 जून) में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा. इसमें कोई शक नहीं कि खुसरो अपने समय की एक महान विभूति थे. उनके जीवन-दर्शन को प्रस्तुत करने और इतिहास की गलत धारणाओं को दूर करने का यह प्रयास निश्चय ही सराहनीय है.

—कुंवर आलोक चंद्र, गोंडा (उ.प्र.)

आत्मनिर्भरता जरूरी

'दानवी जुनून का फैलता दायरा' (30 जून) पढ़ कर लगा कि भारत किसी बर्बर युग की ओर बढ़ रहा है. केवल कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा. दहेज के कोढ़ को दूर करने के लिए समाज के युवा वर्ग को ही आगे आना होगा. लड़कियों को भी चाहिए कि पहले आत्मनिर्भर बनें, तब विवाह की सोचें.

—एल.एन. खत्री, जैसलमेर (राज.)

■ लगता है दहेज प्रथा अब शायद कभी खत्म नहीं होगी. क्योंकि अब यह उन वर्गों में भी तेजी से फैल रही है जो अब तक इससे अछूते थे. आज गैस के जमाने में भी लोग स्टोव इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसे स्टोव जो बहुओं के ही पल्लों और चुन्नियों को पहचानते हैं, सासों और ननदों के पल्लों को नहीं.

—राजेश श्रीवास्तव, (म.प्र.)

प्रशंसनीय प्रयास

'समाधि से समाज सेवा तक' (30 जून) पढ़ा. कांची के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती तथा उडुपी के अडमार मठाधीश स्वामी विभुदेश तीर्थ द्वारा सामाजिक पुनर्रचना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं.

—शिवपूजन तिवारी, उन्नाव (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थायी हल ढूंढ़ें

ऑपरेशन ब्लैक थंडर पर आपकी आवरण कथा 'मर्यादा बहाली की सफल मुहिम' (15 जून) पढ़ी. स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकाल बाहर करने के लिए सरकार एवं पुलिस निश्चय ही बधाई की पात्र है. पर यह भी एक विडंबना ही है कि सिखों के लिए खालिस्तान की मांग वे लोग कर रहे हैं जिनके लिए सिखों के 400 वर्ष पुराने स्वर्ण-मंदिर की पवित्रता और मर्यादा की कोई कीमत नहीं है.

—**भोलानाथ गुप्त,** लिलुआ (प. बंगाल)

■ आपने जिस तफसील के साथ ऑपरेशन ब्लैक थंडर की रिपोर्ट दी, वह काबिले-तारीफ है. कितने दुख की बात है कि चुनावों की घंटी ही सरकार को चेता पाती है. यदि ऐसे कड़े कदम शुरू से ही उठा लिए जाते तो पंजाब की हालत इतनी शोचनीय न होती. ऐसी कार्रवाइयां पूरे पंजाब में व्यापक स्तर पर की जानी चाहिए ताकि वह मरघट बन कर न रह जाए.

—**एस. राजाशेखरन,** नई दिल्ली

■ किसी भी समस्या का समाधान यदि शुरू में ही कर लिया जाए तो परेशानी नहीं होती लेकिन सरकार कोई कार्रवाई तभी करती है, जब समस्या जटिल हो जाती है. भले ही निर्दोष लोग जानवरों की तरह मारे जाते रहें. ऑपरेशन ब्लैक थंडर से सरकार ने लोगों के दिलों में विश्वास का संचार किया है. लेकिन पंजाब की खुशहाली के लिए इसका स्थायी हल ढूंढ़ा जाना चाहिए.

—**जितेंद्र चौरसिया,** गया (बिहार)

■ इस ऑपरेशन में जिस धैर्य व विश्वास से काम किया गया वह तारीफ के काबिल है. परंतु स्वर्णमंदिर पर अधिकार कर लेना ही समस्या का हल नहीं है. पंजाब से आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए भी ऐसे ही दृढ़ इरादों की जरूरत है.

—**पवन खुराना,** हनुमान गढ़ (राज.)

■ स्वर्णमंदिर से आतंकवादियों को खदेड़ने की मुहिम अंततः कितनी सफल रहती है यह तो भविष्य ही बताएगा. आतंकवादी अभी भी गरीब, निरीह और निर्दोष व्यक्तियों का खून बहा रहे हैं. जो कदम सरकार को काफी पहले उठाना चाहिए था वह अब उठाया गया है. ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि स्वर्णमंदिर फिर आतंकवादियों का गढ़ बन गया और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही और सरकार इसका दोष पाकिस्तान के मत्थे मढ़ती रही.

—**जुल्फिकार अहमद,** बीकानेर (राज.)

गले नहीं उतरी

'कसौटी' (15 जून) के अंतर्गत 'स्वागतयोग्य बदलाव' पढ़ा. यह बात गले नहीं उतरती कि बंबई के नवधनाढ्यों की जीवन शैली के प्रदर्शन से विदेशों में भारत की अच्छी छवि बनेगी. केवल आडंबर रचने से देश की गरीबी और भुखमरी नहीं छिप सकेगी. अमेरिकी टेलीविजन कंपनी (सीबीएस) को सरकार द्वारा 'फीचर' बनाने की इजाजत न देना औचित्यपूर्ण ही है.

—**अविनाश वावीकर,** सेंधवा (म.प्र.)

खींचतान का नतीजा

गोरखालैंड आंदोलन नया मोड़ ले रहा है, आपकी रिपोर्ट 'अमन की गुंजाइश नहीं' से यह पता चला. केंद्र सरकार और प. बंगाल सरकार का आंदोलन को फुटबाल समझकर एक दूसरे की ओर ठोकर मारना, आपसी खींचातानी और असफल वार्ताएं ही सुभाष घीसिंग के 'करो या मरो' नारे का कारण है. जहां न्याय नहीं, वहां शांति की कल्पना निरर्थक है.

—**पूर्ण बहादुर क्षेत्री,** गुवाहाटी (असम)

कैंची एक ही हो

'हर कैंची की अपनी कतरन' (15 जून) पढ़कर फिल्म प्रमाणन बोर्ड की विसंगतियों का पता चला. देश के सभी सेंसर बोर्डों की अलग-अलग नीति व मानदंडों की मार अंत में छोटे निर्माताओं को ही सहनी पड़ती है. क्यों न सरकार इन सभी बोर्डों का पुनर्गठन कर एक मुख्य बोर्ड बना दे ताकि सभी फिल्मों को निष्पक्षता से पास किया जा सके.

—**राजेश बाफना,** जयपुर (राज.)

अच्छी शुरुआत

'आजकल' में 'चेहरा बदलेगा, मेकअप भी' (15 जून) पढ़ा. दूरदर्शन ने अपनेआप में जो सुधार लाने की कोशिश की है उसकी सभी को अपेक्षा भी थी. दूरदर्शन अब सरकारी भोंपू की छवि हटाकर जो नई छवि बनाना चाहता है, यह एक अच्छी शुरुआत है. पर देखना यह है कि आगे क्या होता है.

—**किरण मंजू,** हरदा (म.प्र.)

आदर्श अफसर

'राज्य-दर्पण' में 'करिश्माई कप्तान साहब' (15 जून) पढ़कर सुखद अनुभूति हुई कि भ्रष्ट पुलिस विभाग के खिलाफ उन्हीं का कोई अफसर भ्रष्टाचार को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है. काश! सभी महकमों में ऐसा अफसर हो तो शायद हमारा देश स्वर्ग बन जाए.

—**धर्मराज शुक्ल,** अकोला (महाराष्ट्र)

कोई शर्म नहीं

जनता पार्टी पर रिपोर्ट 'ले-देकर संकट टल गया' (15 जून) पढ़ने से भारतीय राजनीति के एक अहम पहलू का खुलासा होता है. भारतीय राजनीति किस तरह व्यावसायिकता, व्यक्तिवाद और भौतिकवाद से ग्रस्त है, इसका पता इसी से चल जाता है कि चोटी के नेता भी पतित काम करने में संकोच नहीं करते.

—**सियाशरण,** डाल्टेनगंज (बिहार)

जमीन की सचाई

'ऊंचे इरादों की कच्ची जमीन' (15 जून) नवोदय विद्यालयों की वास्तविकता दर्शाती है. मगर यह भी पूरी तरह सच नहीं कि 75 फीसदी सीटें देहाती छात्रों के लिए हैं. इन पर भी शहरी छात्र कब्जा करने लगे हैं. तीन साल देहात में पढ़ने वाली शर्त पूरा करने के लिए वे तीन साल पहले से ही किसी गांव के स्कूल में फर्जी दाखिला ले लेते हैं और पढ़ते शहरों में हैं या फिर गांवों के स्कूलों से लगातार तीन साल पढ़ने के फर्जी प्रमाण पत्र ले लेते हैं.

—**मंगतराम नरवाल,** जींद (हरियाणा)

■ नवोदय विद्यालय तो कुछ चुनिंदा प्रतिभाशाली छात्रों के वास्ते हैं. यदि सरकार सचमुच ही शैक्षिक स्तर बेहतर बनाना चाहती है तो स्वयंसेवी संस्थानों को उचित सुविधाएं देनी चाहिए.

—**सुनील पंत,** अल्मोड़ा (उ.प्र.)

■ सरकार की दोहरी नीति से किसे फायदा होगा? सरकार को या छात्रों को? एक ओर खर्चीले नवोदय विद्यालय, दूसरी ओर बिना छत, टाट-बोरी और एक अध्यापक वाले ग्रामीण विद्यालय. जब तक इन ग्रामीण विद्यालयों में सुधार नहीं किया जाएगा तो ग्रामीण छात्र नवोदय के 'स्वप्नलोक' में कैसे पहुंच पाएंगे. —**संजीव कश्यप,** बुबकपुर (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

रैपिडैक्स® इंगलिश स्पीकिंग कोर्स

एक रिकार्ड

3,00,00,000 तीन करोड़ से अधिक पाठकों द्वारा अपनायी गयी भारत की बारह भाषाओं में प्रकाशित सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक

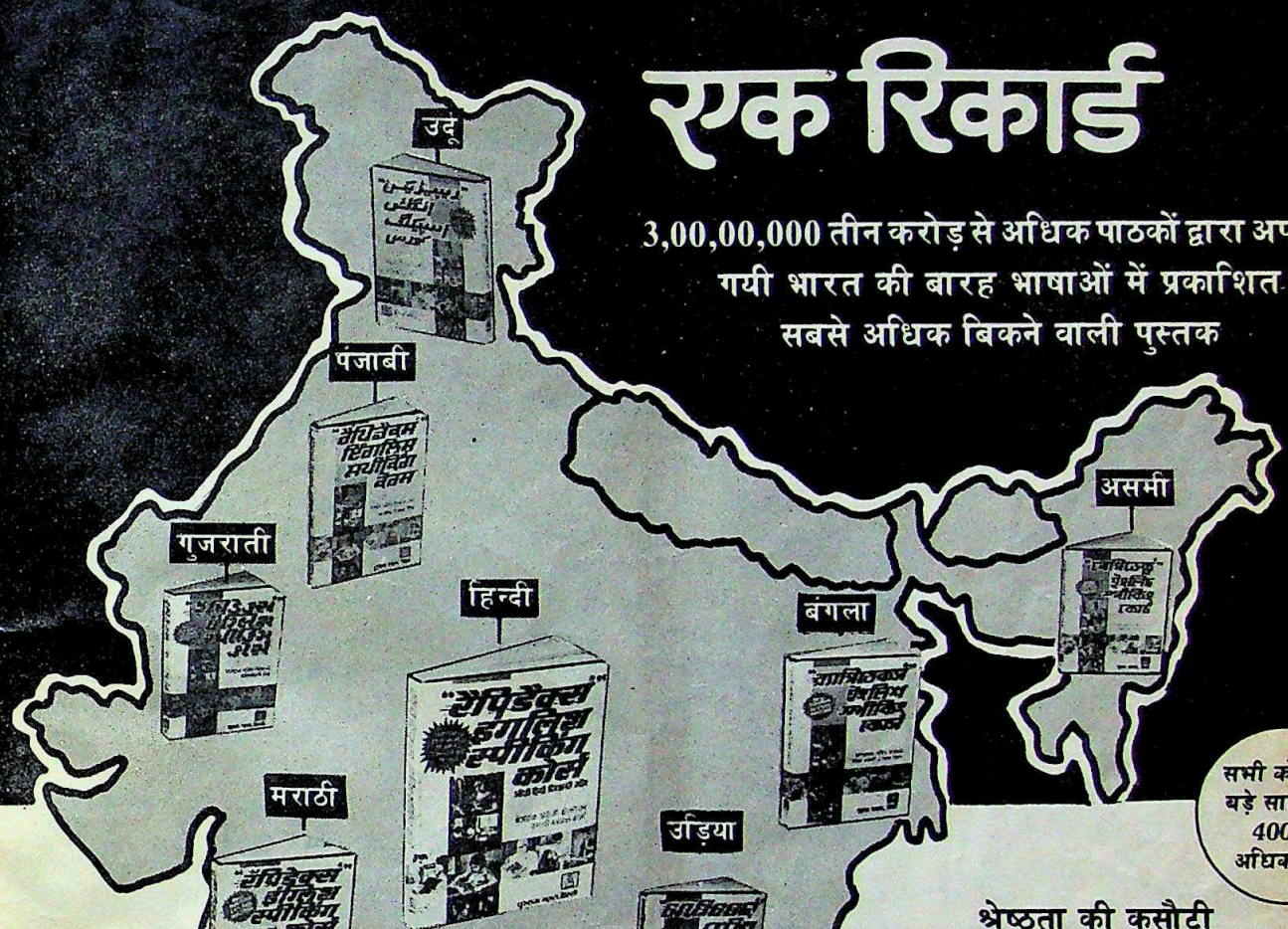

सभी कोर्सों में बड़े साइज़ के 400 से अधिक पृष्ठ

मूल्य : 30/- प्रत्येक
डाकखर्च : 5/-

'रैपिडैक्स' कोर्स सभी प्रमुख बुकसैलरों, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों पर स्थित बुक स्टॉलों पर मिलते हैं।
वी.पी.पी. द्वारा मंगाने के लिए लिखें :–

पुस्तक महल
खारी बावली, दिल्ली-110006.
10-B, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
22/2, मिशन रोड, बंगलौर-560027.

श्रेष्ठता की कसौटी

देशभर के प्रसिद्ध अखबारों की सम्मितियों में से कुछ के अंश :–

•....वार्तालाप शैली में लिखी हुई यह पुस्तक अंग्रेजी बोलना आसानी से सिखा सकती है... अंग्रेजी का सारा आवश्यक ग्रामर भी इस पुस्तक को पढ़कर स्वतः समझ में आ जाता है। **–नवभारत टाइम्स, दिल्ली**

•....बहुत दिनों से एक ऐसी पुस्तक की तलाश थी, जिसको पढ़ते-पढ़ते ही अंग्रेजी बोलचाल का अच्छा-खासा ज्ञान हो जाये और इस कसौटी पर रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग कोर्स खरी उतरी। **–बम्बई समाचार, बम्बई**

•....इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें चुने हुए, दैनिक उपयोग में आने वाले शब्दों की उपयोगी सूची अर्थ सहित दी गई है।... प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषा व व्याकरण सम्बन्धी कुछ आधारभूत बातें अलग से समझाने का प्रयास भी निस्संदेह प्रशंसनीय है। **–जुगान्तर, कलकत्ता**

•....इसमें अंग्रेजी सिखाने की अभ्यास सामग्री इतने बढ़िया ढंग से दी गई है कि कान्वेंट स्कूलों में भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। **–दिनामानी, मद्रास**

•....अंग्रेजी भाषा को शुद्ध और प्रभावपूर्ण ढंग से जितना लिखना जरूरी है, उतने ही प्रभावपूर्ण ढंग से उसके शब्दों का सही उच्चारण तथा सही बोलना भी जरूरी है और ये सब गुण पुस्तक के क्रमवार अभ्यासों में मौजूद हैं। **–गुजरात मित्र, सूरत**

•....आकर्षक आवरण एवं सुन्दर छपाई से सुसज्जित, यह पुस्तक अल्प समय में ही अंग्रेजी सिखाने में सक्षम होने के कारण सभी स्त्री-पुरुषों, विशेषकर गृहिणियों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। **–डेक्कन क्रोनिकल**

•....वास्तव में यह एक बहुत ही उपयोगी कोर्स है। इसमें तमिल जानने वाले बगैर किसी परेशानी के ग्रेजुएट जैसी अंग्रेजी बोल सकते हैं। **–सण्डे स्टैण्डर्ड, मद्रास**

•....रैपिडैक्स कोर्स ही एकमात्र ऐसा विस्तृत कोर्स है, जो हर किसी को 60 दिन में अंग्रेजी बोलना व लिखना सिखा देने में सक्षम है। **–नागपुर टाइम्स, नागपुर**

•....अंग्रेजी सीखने के लिए इसका क्रमवार अभ्यास अपनी एक विशेषता है। **–गुजरात समाचार, अहमदाबाद**

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बताने पर ही क्यों

'नए वात्स्यायन' (15 जून) पढ़ा. आखिर पुलिस शिकायत करने पर ही कार्रवाई क्यों करती है? आज शहरों, कस्बों एवं गांवों में अश्लील साहित्य धड़ल्ले से बिक रहा है और खुलेआम समाज में वासना का जहर घोल रहा है. अश्लील साहित्य के प्रकाशकों और विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस खुद कार्रवाई क्यों नहीं करती?

—जयंत कुमार जोशी, बड़वानी (म.प्र.)

सही राह खोजें

'लड़वैये तैयार' (15 जून) लेख रोचक था. आपने बिलकुल ठीक लिखा है कि सरकार के ढीले रवैये के कारण ही राम जन्मभूमि विवाद एक ज्वालामुखी का रूप धारण करता जा रहा है, जो कभी भी फूट सकता है. अतः अब सरकार को इसे राजनैतिक मुद्दा न बनाते हुए दोनों पक्षों की भावनाओं का आदर करके सही राह खोजनी चाहिए. वरना इस ज्वालामुखी का लावा बहुत कुछ राख कर देगा.

—हुकुम सिंह पंवार, इंदौर (म.प्र.)

■ दुख हुआ कि आजादी के 40 साल बाद भी हम मंदिर और मस्जिदों के लिए लड़ते हैं. मुसलमान कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, हिंदू कहते हैं कि पवित्रता भंग करने वाले को नहीं छोड़ेंगे. इसका सीधा हल यह है कि इस जगह एक अस्पताल बनवा दिया जाए जहां हिंदू-मुसलमान दोनों साथ-साथ इलाज करा सकें.

—संजय दीक्षित, बरेली (उ.प्र.)

तुष्टीकरण का नतीजा

'और चढ़ गया दंगों का रंग' (15 जून) लेख में शिवसेना की सांप्रदायिक गतिविधियों का वृतांत दुखद और चिंतनीय है. दरअसल शिवसेना की लोकप्रियता का बड़ा कारण महाराष्ट्र सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति है, जिसका प्रमाण वह हाल में औरंगाबाद के महापौर के चुनाव के वक्त इंका-मुस्लिम लीग गठबंधन करके दे चुकी है. सरकार को चाहिए कि वह सभी संप्रदायों के प्रति समान नीति अपना कर धर्मनिरपेक्षता का परिचय दे अन्यथा शिवसेना जैसे हिंदूवादी संगठनों की प्रगति रुक नहीं पाएगी.

—शकुनचंद गुप्त, रायबरेली (उ.प्र.)

अनुकरणीय अभियान

'स्वास्थ्य' स्तंभ में 'दिल जलाने के खिलाफ' (15 जून) पढ़ा. महाराष्ट्र सरकार सहित कई कंपनियों का धूम्रपान निषेध में शामिल होना निश्चय ही एक अनुकरणीय अभियान सिद्ध होगा. लेकिन बीड़ी, गुटका, मसाले, जर्दा मिश्रित गुटके की बिक्री व विज्ञापन पर भी केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

—विनोद संघवी, रतलाम (म.प्र.)

अड़ंगे का रवैया

कारोबार के अंतर्गत 'सौतेले बरताव से खफा'(15 जून) में केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष शासित प्रदेशों की योजनाओं में अड़ंगे लगाने के रवैये से बेहद दुख पहुंचा. हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ को ज्यादा अधिकार इसलिए दिए थे ताकि राष्ट्रीय एकता मजबूत रहे, लेकिन अब राजनैतिक पक्षपात के चलते यह भावना मृतप्राय हो गई है. और केंद्र उनका नाजायज फायदा उठा रहा है.

—सुशील सयान, कानपुर (उ.प्र.)

यदि आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए

२५ साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के बाल झड़ रहे हैं....लेकिन उन्हें इसका पता नहीं!

क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आज ही यह परीक्षण कीजिए.

अपने बालों को ज़ोरों से कंघी कीजिए. अगर कंघी पर बाल उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं.

इसका हल है — प्योर सिल्विक्रिन

बालों के झड़ने का कारण है — ज़रूरी अमिनो एसिड्स की कमी — जो आपके बालों की कुदरती ख़ुराक हैं. केवल प्योर सिल्विक्रिन में ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है जो इस कमी को पूरा करता है. इसके कारण है :

१. प्योर सिल्विक्रिन १७ अमिनो एसिड्स का अनोखा मिश्रण है — आपके बालों की कुदरती ख़ुराक.

२. रेडियो ट्रेसिंग का प्रयोग करने वाली विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि प्योर सिल्विक्रिन, बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी पहुँचती है, बालों में कुदरती ख़ुराक की कमी पूरी करती है और बालों को फिर से स्वस्थ बनाती है.

उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की त्वचा पर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का स्वास्थ्य सामान्य नहीं हो जाता.

जल्दी कीजिए! आज ही प्योर सिल्विक्रिन आज़माइए.

प्योर सिल्विक्रिन

OBM/1044/Hin

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूध का दूध, पानी का पानी

मतदाताओं ने अंततः अपना फैसला सुना दिया है. करीब साल भर से चल रहे घोटालों के शोर, राजनैतिक उथलपुथल, भयावह सूखा और इन सब पर काबू पाने की प्रधानमंत्री की कोशिशों पर सात संसदीय और 11 विधानसभाई चुनाव क्षेत्रों के मतदाताओं ने अपनी राय जाहिर कर दी है. उन्होंने उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों, और वे जिन मुद्दों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन सब पर भी अपना फैसला सुना दिया है.

उपचुनाव जितने बड़े पैमाने पर हुए और जिस मौके पर हुए उनके कारण अपनी खास अहमियत रखते थे. ये उपचुनाव आठ राज्यों में हुए जो कि राजनैतिक तौर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाले हिंदीभाषी क्षेत्र में पड़ते थे. आम चुनाव लगभग डेढ़ साल बाद होंगे इसलिए एक तरह से यह उपचुनावों का अंतिम दौर ही था.

इन तमाम बातों के मद्देनजर भारतीय मतदाताओं ने एक बार फिर अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है. उन्होंने एक बार फिर एहसास करा दिया है कि विभिन्न मसलों और अपने हितों से संबंधित मामलों पर वे कितने विवेक से फैसले सुना सकते हैं. इस बार उनका फैसला बहुत ही संतुलित रहा. एक ओर तो उन्होंने सत्ता पक्ष को साफ चेतावनी दी, दूसरी ओर विभाजित विपक्ष को भी पूरा समर्थन नहीं दिया. अपने आप में यह एक अनूठा फैसला है. अब बड़ी पार्टियां अगले बड़े संघर्ष के लिए दमखम जुटाने में लगेंगी.

रेखाचित्र: अजीत नैनन

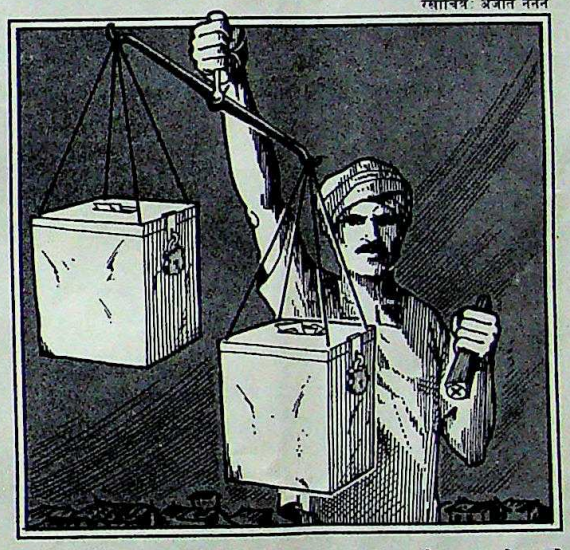

इलाहाबाद के मतदाताओं ने सरकारी प्रचारों से प्रभावित हुए बिना उन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा जिन्हें वे अहम समझते थे. और पश्चिम बंगाल में निश्चित-से हो चुके वाममोर्चे को उन्होंने अपने फैसले से चकित कर दिया. उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में उन्होंने उन मुख्यमंत्रियों के निकम्मे प्रशासन के खिलाफ अपना फैसला सुनाया जो अब तक केवल कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे.

इसमें संदेह नहीं कि जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर मतदान होते रहे हैं और हुए हैं. लेकिन राजनैतिक पार्टियों को बार-बार यह सबक भी मिला है कि इन तमाम प्रभावों के बावजूद समसामयिक मुद्दे मतदान पर निर्णायक असर डालते हैं. इस लिहाज से जहां तक मुद्दों का सवाल है, मतदाताओं ने इस बार दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है. भ्रष्टाचार और बोफोर्स घोटाला मुख्य मुद्दा न होता तो शायद इलाहाबाद के मतदाताओं का फैसला कुछ और हो सकता था. यानी सरकार और कांग्रेस पार्टी अगर यह सोचती है कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से वह इन घोटालों को ढक सकती है तो वह मुगालते में है. उन्हें अगर और ज्यादा व्यापक पैमाने पर मतदाताओं का विरोधी फैसला नहीं सुनना है तो इन मुद्दों को विश्वसनीय तरीके से निबटाना होगा.

दरअसल मतदाताओं ने पिछले एक दशक से भी ज्यादा से बार-बार यह दिखा दिया है कि वे साहस और विवेक से अपना फैसला सुना सकते हैं. 1977 में पार्टी और सरकार की सारी मशीनरी मिलकर भी सत्ता पार्टी को बचा न सकी, 1980 में आपस में लड़भिड़ रहे जपा नेताओं को उन्होंने उनकी औकात बता दी, और 1984 में जब राष्ट्रीय अखंडता पर खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने फिर अपने विवेक का परिचय दिया. हकीकत तो यह है कि जिन मतदाताओं ने राजीव गांधी को और कांग्रेस पार्टी को इतना भारी समर्थन दिया था उन्होंने अब साफ-साफ संकेत दे दिया है कि साढ़े तीन साल के उनके शासन से वे कतई संतुष्ट नहीं हैं, और अगर यही रवैया रहा तो उनका फैसला फिर खिलाफ जा सकता है.

इन सबसे एक बात स्पष्ट होती है कि मतदाता लगातार विकल्प की तलाश में हैं. पहले जब कभी भी उन्हें लगा कि विकल्प सामने है तो उन्होंने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, मसलन पश्चिम बंगाल और केरल में वाममोर्चे के, तो कर्नाटक में जनता पार्टी या आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के पक्ष में. हरियाणा में लगभग संगठित विपक्ष को उसने भारी समर्थन दिया और इन ताजा उपचुनावों में जिस भी विपक्षी उम्मीदवार को गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने समर्थन दिया, मतदाताओं ने उसकी झोली वोटों से भर दी.

यानी विपक्ष के लिए संदेश साफ है कि राजीव सरकार की गलतियों ने उसे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का मौका भले दिया हो लेकिन उसे अपना हिसाब-किताब दुरुस्त कर लेना चाहिए. उसे एक साझा मंच और एक नेता के नीचे संगठित हो जाना चाहिए ताकि मतदाताओं को, जो 1977-79 का दौर नहीं भूल पाए हैं, विश्वास हो सके कि विपक्ष इस बार सचमुच गंभीर है.

और कांग्रेस पार्टी के लिए सबक? राजीव गांधी का चुनावी रिकार्ड इतना दागदार हो चुका है कि छिपाना मुश्किल है. अब तो कांग्रेस पार्टी का संसद में बहुमत देश भर के राजनैतिक माहौल के आगे विरोधाभास ही लगता है. प्रधानमंत्री अगर इस हकीकत की अनदेखी करते हैं तो अपना ही नुकसान करेंगे. राज्यों के चुनावों और लोकसभा के उपचुनावों में उन्हें और उनकी पार्टी को बार-बार शर्म का मुंह ही देखना पड़ा है. मतदाताओं ने एक बार नहीं, बार-बार उनके खिलाफ फैसला सुनाया है. इससे ज्यादा चेतावनी नहीं मिल सकती. अब तो अंतिम परीक्षा ही होगी. संभव है कि आम चुनाव में राजीव और उनकी पार्टी बहुमत हासिल कर ले. लेकिन अंतर निश्चित तौर पर घटेगा. यानी अगले 18 महीने सरकार और विपक्ष दोनों के लिए निर्णायक होंगे. सरकार को चुनौती होगी कुछ कर दिखाने की, तो विपक्ष को अपनी एकता का विश्वास दिलाने की. आम चुनाव में विजय उसी की होगी जो हाल में संपन्न हुए उपचुनावों के नतीजों और मतदाताओं की चेतावनियों से ज्यादा-से-ज्यादा सबक लेगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरिए

यह कूपन और
अपनी चहेती आवाज़ सुनिए:
बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.

बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूँ.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

Walt Disney
डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े
हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

आर.के. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया

● गुलाम नबी आजाद ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? अगर मेरे बेटे-बहू ने गलत किया है तो कार्रवाई कर लें.

■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *नवभारत टाइम्स*

● विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति से बूथ पर कब्जे और धांधली की उम्मीद नहीं थी.

■ **सुनील शास्त्री,** *संडे मेल*

● दूरदर्शन धारावाहिक में राम की भूमिका करने से कोई भगवान नहीं बन जाता.

■ **कमलापति त्रिपाठी,** *आज*

● (मुख्यमंत्री) बीरबहादुर मेरे सामने कुछ नहीं है. उसे तो जब चाहे कान पकड़कर निकाला जा सकता है.

■ **कांशीराम,** *दिनमान*

● मैं इन सब समाजवादियों को जानता हूं, कम्युनिस्टों को जानता हूं. ये भी वही स्कॉच पीते हैं जो मैं पीता हूं.

■ **राहुल बजाज,** *जनसत्ता*

● मेरा नाम भी भजनलाल है! भजनलाल की चक्की चलती धीरे है लेकिन बहुत बारीक पीसती है.

■ **भजनलाल,** *दैनिक ट्रिब्यून*

● कांग्रेस सरकार ने गुमानमल लोढ़ा को मुख्य न्यायाधीश बनाकर उन पर रहम ही किया.

■ **शिवचरण माथुर,** *राजस्थान पत्रिका*

● मैं नगर निगम का वेतनभोगी नौकर नहीं हूं कि हर रोज कार्यालय जाया करूं.

■ **कृष्णनंदन सहाय,** *(महापौर, पटना), हिंदुस्तान*

● अब मैं इस खेल से थक गया हूं. आज अगर आप मुझे बैडमिंटन खेलने को कहें तो मैं साफ इनकार कर दूंगा.

■ **प्रकाश पदुकोणे,** *स्पोर्ट्सवीक ऐंड लाइफस्टाइल*

● यह (फिल्म) इंडस्ट्री किसी के बाप की जायदाद नहीं है. कितना भी बड़ा या छोटा एक्टर हो, एक न एक दिन तो उसे छुट्टी लेनी ही होगी.

■ **मिथुन चक्रवर्ती,** *स्टारडस्ट*

● मेरे बाद अमिताभ ही सर्वश्रेष्ठ है.

■ **शत्रुघ्न सिन्हा,** *फिल्मफेयर*

● अब तो मैं अपने घुटनों के बल झुक भी नहीं सकता. भला हो मेरी 'याहू' वाली छवि का.

■ **शम्मी कपूर,** *मूवी*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पायलट और जहाज

● पुराने पायलट को किस जहाज में उड़ना चाहिए? प्रधानमंत्री कार्यालय आजकल इस सवाल का जवाब खोज रहा है. प्रधानमंत्री की आए दिन होने वाली विदेश यात्राओं के लिए उसे उपयुक्त विमान की तलाश है. राजीव गांधी की सरकारी यात्राओं के लिए 450 सीटों वाले भारी-भरकम बोइंग-

747 विमान के इस्तेमाल की आलोचना को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा छोटा विमान खोजा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री के पूरे अमले (यानी पत्रकारों और सुरक्षा वालों समेत तकरीबन 80 लोगों) को ले जाया जा सके और हर बार भारी-भरकम जंबो विमान पर भरोसा करने की जहमत भी न उठानी पड़े.

पहले इसके लिए 150 सीटों वाले बोइंग-707 का इस्तेमाल करने की बात सोची गई और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कहा गया कि वह इसकी क्षमता पर अपनी रिपोर्ट दे. पर मामला बीच में ही लटक गया क्योंकि पता लगा कि ज्यादातर एअरलाइंस इस जहाज का अब इस्तेमाल नहीं करतीं. इससे भी बड़ी बात कि अब न तो यह जहाज बनता है और न ही इसके कलपुर्जे. यह प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में पहुंचते ही प्रधानमंत्री कार्यालय फिर बोइंग-747 से छोटे विमान की तलाश में भटक रहा है. ऐसा कोई विमान या तो एअर इंडिया से विशेष अनुबंध पर लिया जाएगा या फिर जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उनकी वायुसेना का एक विमान हरदम खड़ा रहता है उसी तरह सिर्फ राजीव के इस्तेमाल के लिए भी उपयुक्त विमान हमेशा खड़ा रखा जाएगा.

नया शगूफा

● इलेक्ट्रॉनिक्स के सूरमा सैम पित्रोदा का प्रस्ताव है कि पांच सरकारी तकनीकी मिशनों की तरक्की पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति बनाई जाए जिसमें तमाम लोग गैर-सरकारी होंगे. इनमें स्वयंसेवी संगठनों के लोग, विकास विशेषज्ञ और हां, वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे. उम्मीद है इस समिति की प्रधानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती को सौंपी जाएगी. हालांकि नामों पर फैसला अभी होना है पर एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है. यह नाम है पूर्व रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह का, जिन्होंने पिछले साल कुछ 'निजी' कारणों से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

निगरानी समिति का असल काम होगा तकनीकी योजनाओं की प्रगति के दावों की जांच करना. विचार यह है कि जांच के नतीजों पर

सभी कार्टून: अजीत नैनन

अखबारों और संचार माध्यमों में लिखा जाए और रिपोर्ट बनाकर सैम पित्रोदा को दे दी जाए ताकि सरकारी दावों की जवाबी जांच हो सके. अचरज नहीं कि अफसरशाही इससे नाखुश है और बड़ी बेकरारी से इस योजना को धूल चटाने की कोशिश कर रही है. पर पित्रोदा अपनी धुन में जुटे हैं.

दूध के जले

● क्या वजह है कि पाकिस्तान में तैनात होने वाले ज्यादातर भारतीय राजनयिक पाकिस्तान को गरियाने लग जाते हैं? इस्लामाबाद में राजदूत रहे नटवर सिंह (अब विदेश राज्यमंत्री) पाकिस्तान की उतनी ही सख्त आलोचना करते हैं जितनी कि वहां नियुक्त मौजूदा राजदूत एस.के. सिंह. कराची में रहे दो

महावाणिज्यदूतों जी. पार्थसारथी, जो अब प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं और आफताब सेठ, जो विदेश प्रचार के संयुक्त सचिव हैं, दोनों के ही मन में पाकिस्तान को लेकर काफी गंभीर शंकाएं रहती हैं.

इसकी एक वजह यह है कि भारतीय राजनयिकों को पाकिस्तानी खुफिया विभाग खासा परेशान करता है. पुलिस वाले चप्पे-चप्पे पर उनका पीछा करते हैं. और तो और, उनके पास आने-जाने वालों को बीच सड़क पर रोककर पूछताछ करते हैं. दूतावास के नौकर शिकायत करते हैं कि आने वाले मेहमानों के बारे में खुफिया विभाग वाले उनसे पूछते हैं. राजनयिकों की बीवियां पिछवाड़े की दीवार फांदकर पड़ोसियों के यहां जाती हैं क्योंकि अगर वे सामने के दरवाजे से गईं तो पड़ोसी की शामत आ जाती है. पाकिस्तानी खुफिया उन्हीं से पूछताछ करने लग जाते हैं. ऐसी कड़वी यादों से दोस्ती का जज्बा नहीं बनता. जबकि उधर दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी राजनयिक मानते हैं कि उनकी निगरानी परेशान करने वाली नहीं होती. शायद यही वजह है कि इनमें से ज्यादातर यहां से जाने के बाद भारत का नाम सुनते ही कोई कड़वी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते.

तोहफे पर असमंजस

● अठारह साल के एक लड़के की सालगिरह पर आपको आमंत्रित किया गया हो तो आप उसके लिए क्या तोहफा लेकर जाएंगे? यह सवाल जटिल तो है मगर आसान भी. वह 18 साल का किशोर प्रधानमंत्री राजीव गांधी का साहबजादा राहुल हो तो जवाब काफी आसान हो जाता है. उसका 18वां जन्म दिन 18 जून को था.

कहा जाता है कि परिवार सबसे उपयुक्त पाठशाला होती है. सो राहुल भी इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च तकनीक के तामझाम की चकाचौंध के प्रेमी अपने पिता पर ही गया है. (राजीव जो किताबें पढ़ते हैं उनमें कंप्यूटर के क्षेत्र में होने वाली नई उपलब्धियों की किताबों की बहुतायत होती है). इसलिए जब राहुल की सालगिरह के कुछ ही दिन बचे तो मौके पर आमंत्रित लोग एक-दूसरे को टेलीफोन करके पूछने लगे

कि राहुल को किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक तोहफा दिया जाए. इनमें ज्यादातर लोग राजीव और सोनिया के पुराने दोस्त थे. मेहमानों में शामिल लोगों के जानकार सूत्रों के मुताबिक फैंसी कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक खेल और रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने हवाई जहाज तोहफे के रूप में देने के सुझाव आए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऐसा भी होता है

■ भला ऐसा भी हो सकता है कि भरे बाजार में किसी सुनार पर उचक्कों का पूरा गिरोह टूट पड़े, दो तीन किलो माल समेत उसका थैला छीनकर वे भाग खड़े हों और कोतवाली के अफसर रपट

सभी कार्टून मंजुला पद्मनाभन

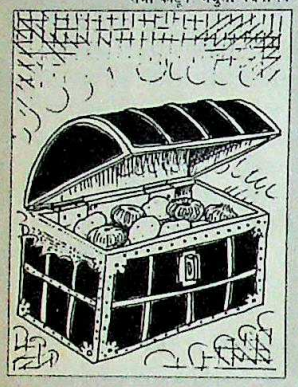

लिखने के बजाए ठहाके मारकर हंसना शुरू कर दें? अगर सचमुच ऐसा होता है तो इसे कानून और व्यवस्था की बरबादी की इंतिहा ही कहा जाएगा. यह 'इंतिहा' पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मऊनाथभंजन कस्बे में हुई.

वहां का एक प्रमुख सर्राफा व्यापारी शाम के समय दुकान बंद करके घर लौट रहा था कि गुंडों के एक गिरोह ने उसे बीच सड़क में ही रोक लिया और लोगों की आंखों के सामने उसका थैला छीनकर भाग खड़े हुए. व्यापारी ने पहले तो शोर मचाया और फिर निकटवर्ती कोतवाली में रपट लिखाने के लिए जा घुसा. आगे-आगे व्यापारी और पीछे-पीछे लोगों का हुजूम जो यह जानने को उत्सुक था कि कितने हजार या लाख रुपए का माल लुट गया. उधर यह खबर कोतवाली तक पहले ही पहुच चुकी थी और वहां के दरोगा भी विवरण जानने को उतावले थे. लेकिन जब व्यापारी ने घटना और माल का विवरण देना शुरू किया तो हंसी के मारे दारोगा साहब का हाल बुरा हो गया. पता चला कि थैले में सोना चांदी नहीं बल्कि आलू और प्याज थे जो व्यापारी ने घर के लिए खरीदे थे. संयोग से असली माल का थैला उस दिन नौकर के हाथ पहले ही घर भेजा जा चुका था.

भीड़तंत्र का कमाल

■ भीड़ की मानसिकता के बारे में अकसर कहा जाता है कि वह विध्वंसक होती है और अच्छे-बुरे का अंतर नहीं पहचान सकती. लेकिन पिछले दिनों गाजियाबाद में गुस्से से उबलती भीड़ ने जिस तरह से एक रिश्वतखोर अफसर की खबर ली उसने एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर दिया. शहर से बाहर हिंडन नदी के निकट एक ट्रक ने सुबह की सैर पर निकले चार युवकों को कुचल डाला. इस पर लोगों की भीड़ ने नाराजगी दिखाते हुए एक ट्रक को जला दिया और आती जाती दूसरी गाड़ियों पर पथराव किया.

इस तोड़फोड़ के बाद भीड़ शहर वापस जा रही थी कि रास्ते में एक चुंगी चौकी पर लोगों ने एक अधिकारी को एक ट्रक ड्राइवर से पैसे लेते देख लिया. पूछताछ करने पर ड्राइवर ने बताया कि चुंगी पर अधिकारियों को रिश्वत देने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता है. अब भीड़ ने पैसा लेने वाले अधिकारी को जा दबोचा. पहले तो उसकी तलाशी ली गई जिसमें लगभग ८०० रुपए निकले. उसके बाद उसकी ऐसी पिटाई की गई कि वह कसम खाकर यह आश्वासन देने के लिए राजी हो गया कि भविष्य में वह रिश्वत नहीं लेगा. इसके बाद पूरी भीड़ के बीच कान पकड़कर कसम

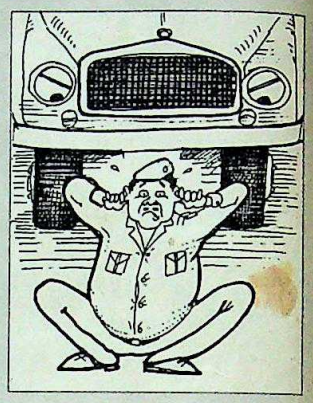

खाते हुए उसने पांच बार उठक-बैठक लगाई. तब कहीं जाकर उसे भीड़ के गुस्से से मुक्ति मिली. इस सौदेबाजी में यह भी तय हुआ कि अफसर से बरामद किए गए रिश्वत के पैसे दान में दे दिए जाएं.

जिंदा हूं इस तरह...

■ पिछले दिनों इलाहाबाद में हुए संसदीय उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को यूं तो एक से एक बड़े नेताओं को देखने का मौका मिला लेकिन उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त में एक व्यक्ति ऐसा था

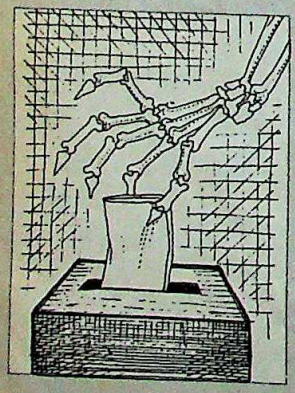

जिसने मतदाताओं की उत्सुकता और कौतूहल के नए पुराने रिकार्ड ध्वस्त कर दिए. लालबिहारी नाम वाले इस उम्मीदवार की एक अनूठी खूबी यह थी कि वह जीवित नहीं बल्कि 'मृतक' था. सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से 12 साल पहले मर चुके इस व्यक्ति को साइकिल चुनाव चिन्ह के अलावा दो सुरक्षा गार्ड भी दिए गए.

लालबिहारी के चुनाव अभियान की एक प्रमुख बात यह भी थी कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने जीवित मतदाताओं के बजाए 'मृतक' नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का एलान किया. लालबिहारी के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में ही ऐसे लोगों की संख्या 10 हजार से ऊपर है जो असल में तो जिंदा हैं पर सरकारी दस्तावेजों में उन्हें 'मृतक' बताया जा रहा है. पिछले 12 साल के दौरान सरकारी रिकार्ड में स्वयं को जीवित सिद्ध करने के लिए वे अफसरों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ खतो-किताबत करने से लेकर विधान परिषद में पर्चे फेंकने और बोट क्लब पर भूख हड़ताल जैसे सारे अस्त्र इस्तेमाल कर चुके हैं. अपने इस चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी 'मृतकों' को एक झंडे तले लाने के लिए 'उत्तर प्रदेश मृतक संघ' की भी स्थापना की है.

जंगल राज

■ पिछले दो तीन साल से चले आ रहे सूखे और गर्मी ने जहां एक ओर मनुष्य के लिए संकट पैदा कर दिया वहां जंगलों में रहने वाले जानवरों के सामने भी जीवन मरण का प्रश्न खड़ा कर दिया. संकट की ऐसी हालत में यदि जानवरों का व्यवहार असामान्य हो जाए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए. बीती गर्मियों में महाराष्ट्र के मेलघाट जंगल क्षेत्र में बंदरों ने जिस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन किया उसे देखकर यह मानना होगा कि बंदर न केवल मनुष्य का पूर्वज है बल्कि उसके व्यवहार में मनुष्य के कई बुरे गुण भी मौजूद हैं.

इस जंगल का दौरा करने वाले एक वन्य प्रेमी रमेश गणोरकर के अनुसार जब जंगल में पानी की कमी हो गई तो वहां बचे एकमात्र पोखर पर बाघों ने कब्जा जमा लिया. इसके बाद जब जंगल के साथ बहती नदी के कुछ गड्ढों में भी पानी कम होने लगा तो उस पर बंदरों के गिरोहों ने कब्जा कर लिया. हालत यहां तक आ पहुंची कि इन गड्ढों से पानी पीने के लिए आने वाले सुअरों, हिरणों, भालुओं और दूसरे जानवरों पर बंदरों ने मिलकर धावा बोलना शुरू कर दिया और गड्ढों पर बंदर परिवारों ने अपना-अपना अधिकार जमाते हुए वहां चौकीदारी शुरू कर दी. लेकिन बढ़ती गर्मी में जब कुछ गड्ढे

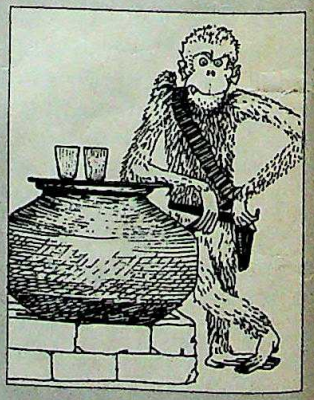

सूख गए तो इन परिवारों में आपसी झगड़े भी शुरू हो गए. गणोरकर के अनुसार इन झगड़ों में इस मौसम के दौरान कम से कम 30 बंदर मारे गए.

संकलन : विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिस देश में लाखों करोड़ों लोगों के पास सिर छिपाने को छत न हो। मौसम की मेहरबानी पर जहाँ के लोग ज़िन्दगी गुज़ारते हों। उसी देश में होती है करोड़ों रुपयों की बरबादी। कारण है हम और आप। हम और आप मिलकर हर साल करते हैं उन करोड़ों रुपयों की बरबादी जिनसे 10 लाख घर इन जैसे जरूरतमन्द लोगों के लिये बनाये जा सकते हैं।

दुख की बात तो यह है कि इतना बड़ा सच हमें छूता तक नहीं। कहीं चुभता भी नहीं। क्योंकि हमारे पास कई ज़रूरी चीज़ें हैं सोचने को-करने को। ऐसी फ़ालतू बातों के लिए भला समय कहाँ? हमारी आँखों पर बंधी लापरवाही की पट्टी हमें कुछ देखने नहीं देती।

2000 करोड़ रु० की बरबादी हर साल हो रही है और ये हम सब मिलकर कर रहे हैं।

सड़कों पर, रसोई-घरों में, कारखानों और खेतों में। हर जगह, हर कहीं होती है पेट्रोलियम की बरबादी। क्योंकि ज़्यादा ईंधन खाने वाले पुराने डिज़ाइन के उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं। सवारी की सही देखभाल नहीं होती। और न ही हमारी आदतों और ड्राईविंग के तरीकों में सुधार।

आपके ज़रा से जागरुक प्रयास से इस फ़ज़ूलखर्ची को रोका जा सकता है। लोगों की सोई हुई चेतना को जगाया जा सकता है। बिखरी हुई आवाज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत बरबादी हो चुकी। अब और नहीं। आइए, अब इसके खिलाफ़ आवाज़ उठायें। अपने अखबारों में लिखें। अपनी कॉलोनी, ऑफ़िस, क्लबों, संस्थाओं—हर तरफ चर्चा करें। काम करने वाले लोगों की सक्रिय टोलियाँ बनायें।

आपकी मदद के बिना कुछ नहीं हो पायेगा। पेट्रोलियम बचाने का संदेश घर-घर तक आपको ही पहुँचाना है।

हम आशा करते हैं कि आप चुप रहने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे।
क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस पन्ने को पलट कर कहेंगे—

"मेरी बला से!"

इस विषय पर आइए हमसे मिलिए। आपके विचारों का स्वागत है।

पेट्रोलियम कंज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन

1008, नई दिल्ली हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110 001 फोन : 331 9066, 331 9066

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भ्रांतियों की भूलभुलैया

अजीबोगरीब आहटों की अनुगूंज आती रही पूरे बीते पखवाड़े. लगा जैसे पहले भी ये अप्रिय आहटें सुनी जा चुकी हों. भारत के राजनैतिक महासमुद्र का मंथन एक बार फिर शुरू हो गया हो जैसे. लेकिन इसके इतने आदी हो गए हैं हम कि अब यह न तो बहुत अर्थवान लगता है और न ही बहुत आशाएं जगाता है. राजनीति अटकलबाजी की अनूठी कला बन गई है जैसे—बदलाव की एक मृगमरीचिका भर.

कोई साल या महीने नहीं बीत गए जब इलाहाबाद से शानदार तरीके से जीते विश्वनाथ प्रताप सिंह को विश्वसनीय विकल्प, दिल्ली की तख्त का दमदार दावेदार माना जा रहा था. लेकिन बीच-बीच में उनके पवित्र प्रायश्चितों के उद्घोष उन्हें उक्त भूमिका के लिए अक्षम ठहरा देते हैं.

रेखाचित्र: अजीत नैनन

राजनीति अटकलबाजी की अनूठी कला बन गई है जैसे— बदलाव की एक मृगमरीचिका भर

उधर राजीव गांधी अपने मोहरों में एक और उलटफेर करते हैं तो गुणी जन उसके नतीजों के आकलन और उसमें छिपे संदेश को पढ़ने में लग जाते हैं. लेकिन सबसे कटु तथ्य यह है कि वे अब किसी को बिसात से हटाने का खतरा नहीं उठा सकते चाहे अदना-सा 'पैदल' ही क्यों न हो. यानी कई कर्जे चुकाने हैं, कई मुगालतों को बने रहने देना है और ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे जहाज में कहीं से भी छेद हो.

फेरबदल के 23 दौर हो चुके हैं और इस क्रम में मंत्री पद की महत्ता का भारी अवमूल्यन ही हुआ है. कभी तो कई मंत्रालयों को एक कर दिया जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद अलग. अयोग्यता के आधार पर मुख्यमंत्रियों की छुट्टी की जाती है लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है. पहले जिन लोगों को मुसीबत मानकर हटाया जाता है उन्हें ही फिर सब कुछ भुलाकर वापस ले लिया जाता है. यानी मजबूरियों के चेहरे हजार!

लेकिन ताजा गतिविधियों के मूल में जो कारक है और वह जो व्यापक संकेत दे रहा है उसे धीरे-धीरे जानबूझकर धुंधलाने की कोशिश की जा रही है. यह संकेत देने वाला और कोई नहीं बल्कि वह गुमनाम मतदाता ही है जो हर बार हकीकतों से रू-ब-रू कराता रहा है. उसे भी दिल्ली की तख्त पर बैठे लोगों की करतूतों या कथित शिक्षित समुदाय को चिंतित करने वाले मुद्दों की पूरी समझ है. उसने आज जिस मौके पर जो चेतावनी दी है वह अपने आप में अहम है. अगले अठारह महीनों में राजीव के लिए मौका है कि वे भ्रांतियों को दूर करें वरना खतरा यह है कि कहीं वे खुद ही भ्रांति न बन जाएं.

अगले अठारह महीनों में राजीव के लिए मौका है कि वे भ्रांतियों को दूर करें वरना खतरा यह है कि कहीं वे खुद ही भ्रांति न बन जाएं

लेकिन मतदाता की यह चेतावनी विपक्षी दलों के लिए भी उतनी ही स्पष्ट है. विपक्ष के लिए कोई उम्मीद है तो वह एक रहने में ही पूरी हो सकेगी. बिखरे, तो उम्मीद भी बिखर जाएगी. और हालांकि यही होता रहा है पर दुखद पुनरावृत्ति ही है कि इसके नेता नेतृत्व की मृगमरीचिका से आज भी उबर नहीं पाए हैं. चतुर चंद्रशेखर हों या अधकचरे अजीत सिंह, किसी को भी शायद नेतृत्व की व्यापक मान्यता नहीं मिलने वाली. फिर भी वे उस व्यक्ति को नेता मानने को तैयार नहीं जिसको मान्यता मिल सकती है.

यानी अंततः फिर वही पुराना सच कि राजनीति का चरित्र ही कुछ ऐसा है जो बदलने को राजी नहीं. देश मतपेटियों पर नजरें लगाए होता है और दोनों ही पक्ष बूथों पर कब्जे और धांधली में लगे रहते हैं. अपराधी बंदूकें लिये चुनाव प्रचार करते फिरते हैं, बड़े नेताओं के साथ घूमते हैं. फिर भी अगले 18 महीनों में जो कुछ होगा, चुनावों के मद्देनजर ही होगा. क्या होगा इसका अंदाज लगाना कोई मुश्किल नहीं— लोक लुभावन नारे, रियायतें और वादे! यानी भ्रांतियों को भरपूर खुराक!

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैलो कहने का नया अन्दाज़

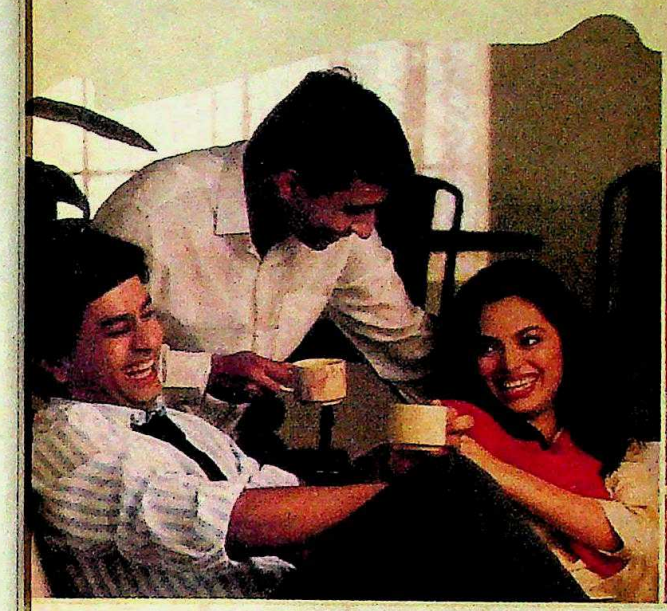

नेस्कैफ़े कॉफी

संग होने की उमंग, जगाए तरंग ऐसे लम्हों में नेस्कैफ़े.

शत प्रतिशत शुद्ध, ताज़ा कॉफी का आनन्द लीजिए. नेस्कैफ़े का खास स्वाद-आपके लिए खास तौर से लाए हैं वो लोग, जिनसे बेहतर कॉफी के बार में और कोई नहीं जानता,

जब सब संग साथ हो ऐसे लम्हों में नेस्कैफ़े ऐसा स्वाद जिस पर दुनिया करे नाज़.

संग होने की उमंग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कांग्रेस (इ) मुश्किलों का

चाहे मुश्किलों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, हमेशा मुस्कराते रहो—प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह सबक जैसे गांठ बांध लिया है. कई उतार-चढ़ाव आए, मतदाताओं का सामना करने के कई मौके आए लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कराहट कभी मलिन नहीं हुई थी. परंतु इस बार मुस्कराहट में वह सहजता नहीं थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और बेफिक्री का भाव भी बनावटी दिख रहा था, ललाट पर परेशानी की हल्की सलवटें छिपाए नहीं छिप रही थीं.

पिछले हफ्ते जब वे सत्ताभिषेक की पावनस्थली, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए अपनी कुर्सी की ओर कदम बढ़ा रहे थे तब उनकी सधी हुई चाल भी इस तथ्य को छिपा नहीं पा रही थी कि आज वे अपने राजनैतिक जीवन के सबसे दुर्धर्ष दौर से गुजर रहे हैं.

अठारह महीने बाद होने वाले आम चुनावों से पहले उपचुनावों के आखिरी दौर में मतदाताओं ने उन्हें अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी दे दी है. 16 जून को संपन्न हुए इन उपचुनावों में सात में से चार (या संभव है पांच भी) लोकसभाई सीटों पर हार सत्ता पार्टी और एक तरह से उसके युवा नेता के मुंह पर करारा तमाचा ही है. और यह याद करके तो इस तमाचे की ताब और भी तीखी लगती है कि ये सातों सीटें कभी उसी की झोली में थीं.

लेकिन राजीव गांधी के लिए हकीकतें इससे भी कहीं ज्यादा कठोर हैं. अगले आम चुनाव में उनका जितना कुछ दांव पर लगा है, शायद किसी और का नहीं. उधर इलाहाबाद में जोरदार जीत ने वी.पी. सिंह को न केवल राजीव के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया है बल्कि विपक्ष में एकता के लिए पर्याप्त उत्साह भी जुटाया है.

इस तरह अचानक दबाव बढ़ने पर राजीव गांधी की प्रतिक्रिया बिलकुल वही थी जिसकी उनसे उम्मीद थी. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से राज्यों की बागडोर छीन ली गई और केंद्रीय मंत्रालयों की रास थमा दी गई. इन उपचुनावों में उत्तर प्रदेश में पार्टी की शर्मनाक हार हुई थी और महाराष्ट्र में बागियों ने पार्टी को खोखला बनाना शुरू कर दिया था. अगले आम चुनावों के नतीजों पर ये दोनों राज्य निर्णायक असर डाल सकते हैं. इन तमाम तथ्यों के मद्देनजर इन दोनों मुख्यमंत्रियों की छुट्टी की गई. और तीसरे राज्य—गुजरात—में भी इस महीने विधानसभा सत्र खत्म होते ही वहां के मुख्यमंत्री की छुट्टी लगभग तय है.

इसी तरह तय था केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल भी. 42 महीनों में

पार्टी सहकर्मियों के साथ नारायणदत्त तिवारी: झिझक

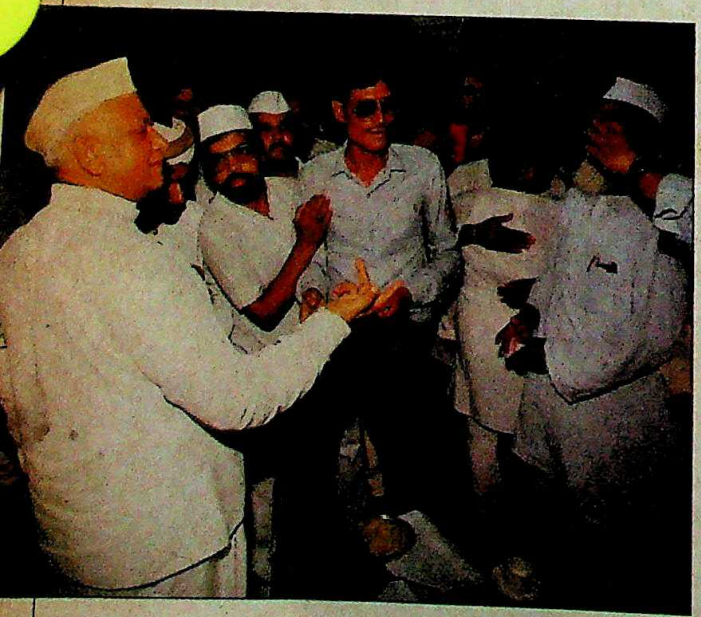

अपने नए मंत्रियों के साथ राजीव: एक और दांव

प्रभात पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहर बरपा

यह 24वां फेरबदल था. इस बार मंत्रिमंडल में छह नए लोग शामिल किए गए, जिनमें दो तो वही हैं जो पहले हटा दिए गए थे. राजीव ने बड़े और छोटे मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल कर दिया. और इस तरह उन्होंने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल बना डाला है. राजीव के सबसे पहले मंत्रिमंडल में कुल 40 मंत्री थे, अब यह संख्या 62 पर पहुंच गई है. यानी 50 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी! और मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करने और निकालने का आलम यह रहा है कि उनके सबसे पहले वाले मंत्रिमंडल के 14 कबीना मंत्रियों में से सिर्फ 8, और 18 राज्यमंत्रियों में से 7 ही आज तक अपनी कुर्सी बचा पाए हैं.

इस बार मंत्रिमंडल को नई शक्ल देने की जद्दोजहद से साफ लगता है कि राजीव के पास विकल्प कितने सीमित हैं. और यह भी कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि यह आखिरी मौका है, समय तेजी से हाथ से निकल रहा है

इन हताशापूर्ण उपायों में एक तरह की हड़बड़ाहट तो दिखती ही है, एक अशुभ संकेत भी प्रकट होता है. हटाए गए मुख्यमंत्रियों—उत्तर प्रदेश के बीरबहादुर सिंह और महाराष्ट्र के शंकरराव चव्हाण—को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने से अब इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या 8 हो गई है. इससे संकेत तो यही मिलता है कि पार्टी में जिसका थोड़ा भी रसूख है उसे नाराज करने का खतरा राजीव नहीं उठा सकते. फिर, कल्पनाथ राय और कमलाकांत तिवारी तक को भी शामिल किए जाने का मतलब तो यही लगाया जा सकता है कि राजीव के पास विकल्प बहुत सीमित हैं. ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि इन दोनों के गैरजिम्मेदाराना बयानों से पार्टी को भारी अपमान का सामना करना पड़ा था.

मंत्रिमंडल को नई शक्ल देने की राजीव की जद्दोजहद से भी साफ पता चलता है कि उनके पास विकल्प कितने सीमित हैं. पहले वे जिस लापरवाह अंदाज में मंत्रिमंडलीय फेरबदल किया करते थे उससे तो उनके विभ्रांत मानस का आभास होता था, पर इस बार की कवायद से यह साफ है कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि बस यह आखिरी मौका है और समय तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है.

प्रमोद पुष्करणा

शुभचिंतकों के साथ पवार : शिवसेना को चुनौती

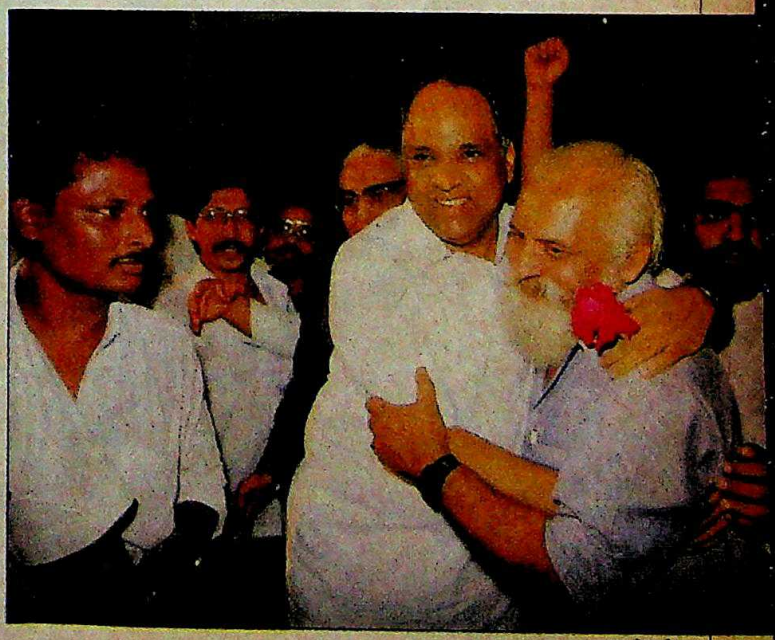

नामस भोजानी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इलाहाबाद

तमाम कोशिशें नाकाम रहीं

प्रख्यात व्यंग्यचित्रकार आर.के. लक्ष्मण ने हमेशा की तरह फिर बहुत सटीक चित्रण किया था. सड़क के किनारे एक भारी-भरकम टैंक ध्वस्त पड़ा है. तोप की नली से धुंआ निकल रहा है. विश्वनाथ प्रताप सिंह एक मोटरसाइकिल पर चले जा रहे हैं. तोप की नली के अंदर सुनील शास्त्री एक वाकी-टाकी लिए हुए कह रहे हैं, "राजीव, उसने अपनी मोटरसाइकिल से मेरी तोप को टक्कर मार दी और भाग गया..."

इलाहाबाद में पिछले पखवाड़े की चुनावी हार बहुत ही अपमानजनक रही. 1984 से अब तक इतनी बुरी तरह कोई भी लोकसभाई सीट नहीं गंवाई गई. 1984 के चुनाव में अमिताभ बच्चन राजीव लहर पर सवार होकर भारी मतों से विजयी हुए थे. तब से यह सीट राजीव की अमेठी सीट के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी.

लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सबसे दुखद बात यह रही कि यह सीट उस व्यक्ति—विश्वनाथ प्रताप सिंह— ने जीत ली जिसे इंका अपना कट्टर दुश्मन मानती है.. इंका ने अपने तमाम बड़े नेताओं को वहां चुनाव प्रचार में जुटा दिया और मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के भी प्रयास किए गए. फिर भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को शानदार विजय मिली. उनकी झोली में वैध वोटों का 54 फीसदी गिरा और वे 1.10 लाख वोटों के अंतर से जीते. उनके पहले 1984 के आम चुनाव में अमिताभ बच्चन ने यहां से 1.87 लाख वोटों से रिकार्ड जीत हासिल की थी. विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुकाबले खड़े सुनील शास्त्री कुल मतदान का सिर्फ 24.7 फीसदी यानी 92,221 वोट ही पा सके. इस निर्वाचन क्षेत्र में इतने कम वोट इससे पहले किसी इंका उम्मीदवार को नहीं मिले थे.

इस महत्वपूर्ण राज्य में इंका की पराजय में जो भी कोर-कसर बाकी थी, वह टांडा (फैजाबाद) और छपरौली (मेरठ) विधानसभाई सीटों पर भी हार से पूरी हो गई. उससे भी ज्यादा सदमे वाली बात यह रही कि जितने वैध वोट पड़े, उसका सिर्फ 27.7 फीसदी ही इंका उम्मीदवारों को मिला. इसके उलट, विपक्षी उम्मीदवारों को 51.4 फीसदी वोट मिले. इलाहाबाद की हार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जातिगत आधार पर वोट बांटने में भी इंका नाकाम रही.

इंका के इरादों का संकेत उसी समय मिल गया था जब इंका ने कायस्थ जाति के शास्त्री को अपना उम्मीदवार बनाया. इसके बाद विभिन्न जातियों के एक दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को अपने-अपने समुदाय को प्रभावित करने के लिए इलाहाबाद भेजा गया. मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद और सांसद सलीम शेरवानी लगभग एक महीने तक यहां डेरा डाले रहे. बीरबहादुर ने ठाकुरों के इलाकों में घूमने का काम संभाला था तो केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी बंगालियों को बरगलाने के लिए 10 दिन तक दौड़ते घूमते रहे.

लेकिन यह रणनीति फुस्स साबित हुई. 16 जून को बंगाली, हरिजन, मुसलमान, ठाकुर और पिछड़ी जातियों समेत सभी प्रमुख समुदायों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के पक्ष में अपने वोट दिए. उन्होंने पांच में से दो विधानसभाई हलकों— बारा और उत्तरी इलाहाबाद में इंका उम्मीदवार के पक्ष में भारी मतदान किया. यहां तक हरिजन वोटों का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कांशीराम और जनमोर्चा उम्मीदवार विश्वनाथ प्रताप सिंह को 45-45 फीसदी और शास्त्री को बाकी 10 फीसदी मिले. वी.पी. सिंह कहते हैं, "इस चुनाव में मेरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि है कि मैं मतदान को सांप्रदायिक या जातीय स्तर से ऊपर रख पाने में कामयाब रहा. हमारा चुनाव प्रचार राष्ट्रीय मुद्दों और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के भ्रष्टचार पर केंद्रित रहा."

हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंहः इंका को कड़ी शिकस्त

मतदान के एक हफ्ता पहले इंका का चुनाव अभियान अचानक ठंडा पड़ गया. इससे यह साफ हो गया कि आखिरी क्षणों में उसने यह तय कर लिया था कि हार का अंतर किसी भी कीमत पर कम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करना है. उसने मतदाताओं को डराने-धमकाने या मतदान में धांधली करने की रणनीति बनाई. जनमोर्चा कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए अपराधियों को जेलों से रिहा कर दिया. 5 जून को इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी और तीन दूसरे लोगों को यहीं के जयनारायण सिंह ने बुरी तरह पीटा. जयनारायण के खिलाफ कई मामले पहले से ही दर्ज हैं.

13 जून को दूसरी घटना हुई. इंका की रणनीति बनाने वाले बीरबहादुर सिंह, आजाद, सीताराम केसरी और केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संतोष मोहनदेव ने जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बुलाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल के साथ आए 200 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया पर जिला मजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया.

इंका के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव के दो दिन पहले पार्टी के रणनीतिज्ञों ने जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से 15-16 जून की रात होने वाली 'कार्रवाई' में सहयोग करने के लिए कहा. इस योजना के तहत निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती 55 मतदान केंद्रों में से हरेक में दो मतपेटियों में मुहर लगे मतपत्र डाले जाने थे. जिला मजिस्ट्रेट बैठक से उठकर चले गए और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा कि इंका इस तरह की मदद मांग रही है. जिला मजिस्ट्रेट ने सभी 937 मतदान केंद्रों के निर्वाचन अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी कि मतपेटियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे. ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए कि मतपेटी लेकर भागने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को गोली मार दी जाए, भले ही वह किसी भी राजनैतिक पार्टी का क्यों न हो. और 15-16 जून की रात घटी कुछ घटनाओं से इंका की योजना का भंडाफोड़ भी हो गया. 16 जून को तड़के 3 बजे लगभग 15 हथियारबंद लोग तीन कारों से सतपुड़ा गांव के दो मतदान केंद्रों पर पहुंचे. उन्होंने बंदूक की नोक पर निर्वाचन अधिकारी आर. श्रीवास्तव से मतपत्र ले लिए और उन पर मुहर लगाकर उन्हें मतपेटियों में डाल दिया.

दूसरे दिन सवेरे श्रीवास्तव ने उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को बता दिया कि बंदूकधारियों ने क्रमांक 391118 से लेकर 391450 वाले 332 मतपत्रों पर इंका के पक्ष में मुहर लगाई और उन्हें मतपेटियों में डाल दिया. लेकिन जनमोर्चा नेता अरुण नेहरू ने, जो मौका-ए-वारदात पर सवेरे 11 बजे पहुंच गए थे, इस बात पर जोर दिया कि बंदूकधारियों ने इन दोनों मतदान केंद्रों के कुल 4,000 मतों में से 836 पर मुहर लगाई. इसी तरह, मिर्जापुर की सीमा पर एक मतदान केंद्र में मतदान शुरू होने के तुरंत बाद कुछ हथियारबंद लोगों ने मतपत्रों पर मुहर लगानी शुरू कर दी. उन्होंने कुल 28 मतपत्रों पर मुहर लगाई. बाद में अधिकारियों के पास इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई. एक दूसरी घटना में हथियारबंद लोगों के एक गिरोह ने हाटा मतदान केंद्र के सामने खड़े लोगों की एक भीड़ पर दो देसी बम फेंके. इससे एक 10 वर्षीय बालक सत्तन बुरी तरह घायल हो गया.

लेकिन वी.पी. सिंह बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी तैयार थे. बाद में उन्होंने कहा, "मुझे पहले से ही आशंका थी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष यह अच्छी तरह जानते थे कि मतपत्रों की निष्पक्ष लड़ाई में इंका कहीं भी नहीं टिक पाएगी."

—दिलीप अवस्थी, इलाहाबाद में

राम शंकर सिंह

इलाहाबाद में अरुण गोविल: धार्मिक भावनाएं भुनाने की भोंड़ी कोशिश

मतदाताओं की धार्मिक भावनाएं उभारने की भोंड़ी कोशिश में कांग्रेस ने 'रामायण' के 'राम' अरुण गोविल से भी चुनाव प्रचार करवाया. लेकिन इससे न तो पार्टी का मकसद ही सधा, न छवि ही सुधरी

तमिलनाडु के कामयाब और हौसला बुलंद करने वाले दौरे के दो दिन बाद तक राजीव ने मुलाकातियों के पहले से तय सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और पार्टी नेताओं, अपने विश्वासपात्र वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी सांसदों से गुफ्तगू करते रहे. लेकिन दिलचस्प और उल्लेखनीय बात तो यह है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष होने के नाते न तो इंका संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और न ही पार्टी कार्यकारिणी की. आखिरी बाजी खेलने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद अपने प्रज्ञाचक्षुओं और कुछ चुनींदा विश्वासपात्रों पर ही भरोसा करना बेहतर समझा.

आगामी महीनों में भी उन्हें समुचित और संतुलित स्वविवेक और सलाहों की जरूरत पड़ेगी. उनके अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए यह निहायत जरूरी होगा. पहली नजर में तो यह ताजा फेरबदल किसी सोची-समझी रणनीति का आभास देता है. कुछ नामों को छोड़ दें तो अधिकांश नियुक्तियां बहुत बेमतलब नहीं लगतीं. वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग शंकरराव चव्हाण के हवाले किया गया है. उन्हें एक ऐसा व्यक्ति माना जाता रहा है जो शक्तिशाली व्यवसायी गुटों के दबाव में नहीं आएगा और जिसे भ्रष्ट करना भी मुमकिन नहीं.

सख्ती और स्वच्छता के मामले में चव्हाण की छवि भी वी.पी. सिंह जैसी ही है. इसलिए संभव है कि एक बार फिर आर्थिक अपराधियों, कर चोरों पर हमला बोला जाएगा ताकि सरकार की अमीर समर्थक छवि मिटाई जा सके. योजना मंत्रालय माधव सिंह सोलंकी को सौंपा गया है जिनमें आठवीं पंचवर्षीय योजना को आकार देने की पर्याप्त क्षमता है. इसी तरह विदेश मंत्रालय में पी.वी. नरसिंह राव की वापसी का स्वागत ही होगा. इस प्रकार विभागों के दूसरे बंटवारे यही संकेत देते हैं कि राजीव ने विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपचुनाव के नतीजे

निराशा का नाद

इलाहाबाद की हार जहां इंका के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक रही, वहीं दूसरे छह संसदीय और 11 विधानसभाई उपचुनावों के नतीजों से भी उसे मामूली राहत ही मिली. मजे की बात यह है कि 1984 के आम चुनाव में ये सभी लोकसभा सीटें उसकी झोली में पड़ी थीं.

इंका को दो ही स्थानों पर उल्लेखनीय सफलता मिली. राजस्थान में पाली लोकसभा सीट उसने बरकरार रखी जबकि मेघालय में तूरा संसदीय क्षेत्र वह, कम अंतर (77,568) से ही सही, हथियाने में कामयाब रही. पश्चिम बंगाल की बाराबानी विधानसभा सीट तो उसके लिए मुनाफे का सौदा रही.

बदतर तो यह है कि इंका जिन जगहों पर अपनी हालत सुधार पाई है वहां भी उसकी बढ़त पांच फीसदी से कम रही. इलाहाबाद में 1984 में अमिताभ बच्चन को मिले मतों से इस बार वह 44.61 फीसदी मत खो बैठी. गुजरात के गोधरा क्षेत्र में यह गिरावट 27 फीसदी रही, हरियाणा के सिरसा में 19 फीसदी.

गुजरात में संयुक्त विपक्ष की ताकत का अंदाज मिला. वहां के गोधरा में विपक्ष के साझा उम्मीदवार, जनता पार्टी के 48 वर्षीय शांतिलाल पटेल ने इंका के 35 वर्षीय उदय सिंह बारिया को 40,000 मतों से हराया. उधर सौराष्ट्र के मालिया विधानसभा हलके से विपक्ष के साझा उम्मीदवार, भाजपा के देवानंद सोलंकी जीते. यहां इंका ने 23.47 फीसदी मत खोए.

फिर सिरसा में लोकदल के हेतराम को सीधे मुकाबले में इंका की शैलजा कुमारी से 1.15 लाख मत अधिक मिले. उधर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के टांडा विधानसभा हलके में इंका को हालांकि 4.58 फीसदी मत अधिक मिले पर वहां मुस्लिम मजलिस ने एक तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके इंका के ही वोट काटे.

लेकिन विपक्ष को कड़वा सबक राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र में मिला जहां भाजपा की ओर से स्थानीय हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा को उतारने के बावजूद इंका के 2.02 लाख मतों के मुकाबले उन्हें 1.63 लाख मत ही मिल पाए.

राजस्थान में पाली संसदीय क्षेत्र और खेतड़ी विधानसभा हलके में इंका के काबिज होने से भाजपा के लिए निश्चय ही परेशानी खड़ी हो गई है. वह पहले इन स्थानों पर लगातार तीन बार से जीतती आ रही थी. इस हार का एक कारण तो विधानसभा में पार्टी के नेता भैरों सिंह शेखावत और राज्य इंका अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी के बीच आपसी मनमुटाव होना है.

अंदरूनी झगड़ा भाजपा ही नहीं इंका को भी ले डूबा है. मध्य प्रदेश में तो उपचुनाव के नतीजे के बाद भी एक तरफ अर्जुन सिंह और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रियों माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा के समर्थकों के बीच घमासान जारी है. सिंधिया और वोरा खेमा ग्वालियर की लश्कर (पूर्वी) सीट पर भाजपा के मतों में 3.74 फीसदी की कमी लाने का श्रेय लेता है.

उधर खरसिया में खुद अर्जुन सिंह को 13 फीसदी मत कम मिलने का मुद्दा भी चर्चाओं में है. राज्य भाजपा अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा कहते हैं, "उनकी जीत तो हार से भी ज्यादा अपमानजनक है." 1977 में इस आदिवासी बहुल हलके के बनने के समय से ही इंका इस पर 20,000 से अधिक मतों से जीतती आई है. साथ ही इस बार अर्जुन सिंह के मुकाबले भाजपा के प्रत्याशी कोई जाने-माने नेता नहीं थे. महत्वपूर्ण तो यह है कि इंका की झोली से आदिवासियों, हरिजनों और मुसलमानों के वोट खिसक गए.

मेघालय के तूरा संसदीय क्षेत्र में इंका के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री विलियमसन संगमा की विजय आश्चर्यजनक नहीं है. पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र में विप्लवी समाजवादी दल की विजय अप्रत्याशित नहीं थी, हालांकि वहां पिछले साल के 13,567 मतों के मुकाबले इस बार 22,298 मतों के रिकार्ड अंतर की उम्मीद निश्चय ही नहीं थी.

लेकिन यह जीत खुशी का कारण नहीं बनी. वाम-मोर्चा में आरएसपी की वरिष्ठ सहयोगी माकपा को राज्य के बेहद औद्योगिक जिले बर्दवान के बाराबानी में जबर्दस्त धक्का लगा. इस क्षेत्र के 48 फीसदी गैर-बंगाली इंका के परंपरागत समर्थक रहे हैं. पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में माकपा की जीत का अंतर गिरता जा रहा था. इस बार उसे 651 मतों से मात मिली.

और सत्ताधारी दल के लिए चौतरफा निराशा के समुद्र में यही एकमात्र आशा का द्वीप दिखता है.

—डेविड देवदास, उदय माहूरकर, नरेंद्र कुमार सिंह और ब्यूरो रिपोर्ट

तालिका: राजीव मदान

इंका की स्थिति

संसदीय क्षेत्र	(दिसंबर) 1984	1988	अंतर
इलाहाबाद	68.21	23.6	−44.61
गोधरा	60.18	39.16	−21.02
सिरसा	54.66	35.68	−18.98
पाली	44.28	44.07	−00.21
तूरा	74.30	63.44	−10.86
उधमपुर	56.98		नतीजा उपलब्ध नहीं
फरीदाबाद	54.01		नतीजा उपलब्ध नहीं

राज्य विधानसभा उपचुनाव

चुनाव क्षेत्र	1985	1988	अंतर
गुजरात			
मालिया	56.19	32.72	−23.47
द्वारिका	39.92	41.24	+01.32
उत्तर प्रदेश			
टांडा	30.5	35.08	+04.58
छपरौली	37.5	36.71	−00.79
मध्य प्रदेश			
खरसिया	66.69	53.64	−13.05
गोहद	57.61	55.30	−02.31
लश्कर (पूर्व)	42.13	45.87	+03.74
प. बंगाल	**1987**		
कुमारग्राम	41.79	35.00	−06.79
बाराबानी	46.07	47.58	+01.51

सभी अंक प्रतिशत में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को योग्य हाथों में सौंपने की कोशिश की है. जैसे दिनेश सिंह को एक बार फिर वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है, शिवशंकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और अनुभवी मजदूर नेता बिंदेश्वरी दुबे को श्रम मंत्रालय. राजीव ने कहा है कि वे खुद राजनैतिक कार्यों के लिए कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहेंगे.

राव को विदेश मंत्रालय सौंपकर और शीला दीक्षित को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करके (पहली बार) राजीव ने यह एहसास कराने की कोशिश की है कि वे फिर अपनी आस्तीनें चढ़ाकर मुश्किलों से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार होना चाहते हैं. दीक्षित की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में राजैनतिक सूचनाओं पर निगरानी रखने के लिए की गई है. बताया जाता है कि वे विभिन्न मंत्रालयों के राजनैतिक आकाओं के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेंगी.

उपचुनावों के नतीजों के बाद राजीव ने अपनी प्रतिक्रियाओं से कुछ ऐसा आभास देने की कोशिश की कि वे कतई परेशान नहीं हैं. लेकिन कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में लेने का फैसला जिस तरह से किया गया उससे उनकी हताशा भरी अफरातफरी छिपाए न छिप सकी. सच तो यह है कि पूर्व वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने और शरद पवार को महाराष्ट्र की बागडोर सौंपने का फैसला जिस समय किया गया उस समय वे दोनों अपने-अपने राज्यों की राजधानियों से कहीं दूर थे. तिवारी लंदन में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ बातचीत कर रहे थे. इन वार्ताओं को अधूरा ही छोड़कर उन्हें एअर इंडिया की सबसे पहली उड़ान से दिल्ली रवाना होना पड़ा. उधर पवार अपनी पत्नी और बेटी के साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे थे और उन्हें भी किसी तरह खोजकर जल्दबाजी में राजधानी पहुंचने का संदेश पहुंचाया गया.

इं का शासित दूसरे राज्यों में कुछ कर पाना राजीव के बस में नहीं रह गया है. गुजरात में चौधरी या ओडीसा में पटनायक का कोई विकल्प नहीं मिल रहा इसलिए उनके मामले पर फैसले में देरी हो रही है

दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें नई जिम्मेवारी सौंपी जाएगी. लंदन जाने से पहले तिवारी कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री से मिले भी थे पर उन्हें तब प्रधानमंत्री ने इस बात का हल्का-सा संकेत भर भी नहीं दिया था कि वे किसी तरह का बदलाव करने जा रहे हैं. पवार को भी लेशमात्र उम्मीद नहीं थी कि उन्हें शंकरराव चव्हाण की गद्दी सौंप दी जाएगी. और तो और, चव्हाण ने भी बाद में स्वीकार किया कि दिल्ली पहुंचने के बाद ही उन्हें फैसले की जानकारी मिली.

राजनैतिक विसंगतियों और उलझनों से जो माहौल बन गया था उससे यही लग रहा था कि राजीव भारी जोखिम भरा खेल खेल रहे हैं. उन्होंने चव्हाण से कहा कि उन्हें हटाने के लिए असंतुष्टों के कारण जो दबाव बढ़ रहा है उसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता. लिहाजा वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें. चव्हाण ने एक अनुशासित पार्टी नेता की तरह आलाकमान की आज्ञा का तुरंत पालन किया लेकिन वे यह देखकर दंग रह गए कि इनाम के तौर पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण कुर्सी सौंप दी गई है.

मगर बीरबहादुर सिंह के साथ राजीव का व्यवहार अपेक्षाकृत रूखा रहा, मानो वे उन्हें इलाहाबाद की हार के लिए दंड देना चाहते हों. राजधानी में लगातार तीन दिन तक इंतजार करवाने के बाद उन्हें राजीव से थोड़ी देर के लिए ही बातचीत का अवसर दिया गया. लेकिन इस बातचीत में राजीव ने देश के सबसे बड़े प्रांत में मिले चुनावी सदमे का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि साफ-साफ शब्दों में उन्हें फैसला सुना दिया गया, "बीरबहादुर जी आपकी यहां जरूरत है और आप तुरंत इस्तीफा दे दें."

बदलते राजनैतिक समीकरणों की सटीक समझ रखने वाले माधव सिंह सोलंकी को भी सुबह 7.30 बजे टेलीफोन से फैसले की जानकारी दी गई और 11.00 बजे राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. के.के. तिवारी और कल्पनाथ राय को भी उनके रहनुमा इस्पात एवं खानमंत्री माखन लाल फोतेदार से इसकी खबर मिली. राजनैतिक हताशा को छिपाने की कोशिश करते हुए इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा,

भवान सिंह

प्रमोद पुष्करणा

"इस तमाम फेरबदल का फैसला तो उपचुनावों के नतीजे आने से पहले ही कर लिया गया था. अब इसके बाद राज्यों में हमारे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में वरिष्ठ पार्टी नेता."

पार्टी की छवि आज जिस कदर धूमिल हो गई है उसे सुधारने के लिए राजीव और उनकी पार्टी के आकाओं को इससे कहीं ज्यादा प्रभावी उपाय करने होंगे. 'द हिंदू' अखबार में बोफोर्स घोटाले से संबंधित नए रहस्योद्घाटन इससे ज्यादा बुरे मौके पर नहीं हो सकते थे. मगर मतदाताओं ने तो इससे पहले ही अपनी ओर से कड़ी चेतावनी दे दी थी. आठ राज्यों (मुख्यत: हिंदी क्षेत्र) के 10 लाख से अधिक मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे इंका से नाराज हैं. पिछले पखवाड़े मिली मात ने त्रिपुरा और नगालैंड में इंका की जीत के असर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'मार्ग' द्वारा मतदान-बाद सर्वे

कारगर अनुमान

इलाहाबाद उपचुनाव के मतदान के दिन मार्केटिंग ऐंड रिसर्च ग्रुप (मार्ग) ने इस चुनाव क्षेत्र में 'मतदान-बाद' (मतदान करके निकल रहे मतदाताओं की राय जानने का) सर्वे किया. 'मार्ग' और चुनाव विशेषज्ञ प्रणय राय द्वारा संयुक्तरूप से किए गए इस सर्वे का मकसद मतदान के वास्तविक रुख का पता लगाना था. हालांकि विकसित देशों में इस तरह का सर्वे आम बात है लेकिन भारत में यह पहली बार किया गया. इस मतदान-बाद सर्वे से साफ पता चल गया था कि वी.पी. सिंह की भारी जीत होगी. उनकी जीत एक लाख मतों के अंतर से आंकी गई थी. इस आकलन से यह एकदम साफ हो गया है कि भावी चुनावों में भी इस तरह के सर्वे की उपादेयता बनी रहेगी.

इसमें मानक प्रक्रिया अपनाई गई. इलाहाबाद में 'मार्ग' के सर्वेक्षणकर्ताओं ने पांच विधानसभा क्षेत्रों (इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, करछना, बारा और मेजा) में कुल मिलाकर 3,594 मतदाताओं से बातचीत की. यह बातचीत ठीक उस वक्त हुई जब मतदाता वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर आए. उनसे पूछा गया कि उन्होंने किसको वोट दिया, और उनकी धर्म और जाति क्या है. उनकी उम्र का अंदाज भी लगाया गया.

'मार्ग' के 20 सर्वेक्षणकर्ता पांच कारों से (हर विधानसभा हलके के लिए एक) चुनाव क्षेत्र के कोने-कोने में चले गए. शाम को उनके इलाहाबाद लौटने के बाद 'मार्ग' विशेषज्ञों ने नतीजों का अनुमान लगाया और अपने मुख्य कार्यालय दिल्ली में फोन से इसकी सूचना दी. ऐन मतदान के दिन किया गया यह सर्वे मतदाताओं का रुख भांपने में बेहद कारगर साबित हो सकता है. इससे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करने वाली वजहों और मतदान की प्रवृत्ति की भी जानकारी मिल सकती है. प्रस्तुत है इस सर्वे के नतीजों का लेखाजोखा:

नतीजे

'मार्ग' के इस सर्वे ने संकेत दे दिया था कि वी.पी. सिंह भारी अंतर से जीतेंगे. लेकिन इस सर्वे से दो प्रमुख उम्मीदवारों—वी.पी. सिंह और सुनील शास्त्री को मिलने वाले वोटों के प्रतिशत का तो लगभग सही-सही अंदाज लगाया जा सका लेकिन तीसरे उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के कांशीराम की ताकत का अंदाज ठीक-ठीक नहीं लगाया जा सका. उसे कम आंका गया.

शहरी-ग्रामीण

वी.पी. सिंह शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी आगे थे. हकीकत में तीनों प्रमुख उम्मीदवारों के तुलनात्मक प्रभाव का अंतर शहरी और ग्रामीण इलाकों में तकरीबन समान पाया गया. वैसे, सवालों का जवाब न देने वालों का प्रतिशत शहरों के मुकाबले गांवों में कहीं ज्यादा था.

जाति

वोटों के जातिगत बंटवारे को लेकर वैसे तो बहुत अटकलें लगाई जा रही थीं लेकिन 'मार्ग' के इस 'मतदान-बाद' सर्वे ने हकीकत को पूरी तरह उजागर कर दिया. जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, ज्यादातर ठाकुरों ने वी.पी. सिंह का समर्थन किया. विपक्ष के साझा उम्मीदवार ने मुसलमानों पर इंका की पकड़ को भी तोड़ दिया और उनके 76 फीसदी वोट हासिल किए. यहां तक कि वी.पी. सिंह ब्राह्मणों के भी दो तिहाई वोट हासिल करने में कामयाब रहे.

मात खाए सुनील शास्त्री को अपनी कायस्थ जाति के मतदाताओं की सहानुभूति जरूर मिली. दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले उन्हें ही कायस्थों का सबसे ज्यादा समर्थन मिला लेकिन यहां भी वी.पी. सिंह उनसे कुछ थोड़े ही पीछे रहे (49 फीसदी के मुकाबले 45 फीसदी).

लेकिन इंका को सबसे बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने दिया. उन्होंने उसके पारंपरिक वोट बैंक—हरिजनों—के तकरीबन 60 फीसदी वोट बटोर लिए. उनके बाद वी.पी. सिंह 26 फीसदी वोट और सुनील शास्त्री 15 फीसदी वोट ही हासिल कर पाए.

राजीव मदान

नतीजे

	'मार्ग' 'मतदान-बाद' सर्वे	वास्तविक
वी.पी. सिंह (जनमोर्चा)	54	52
सुनील शास्त्री (इंका)	24	24
कांशीराम (बसपा)	13	18
अन्य	1	6
इनकार किया	8	—

सभी आंकड़े प्रतिशत में

शहरी-ग्रामीण

	शहरी	ग्रामीण
वी.पी. सिंह	59	58
सुनील शास्त्री	25	27
कांशीराम	14	14
अन्य	2	1
वी.पी. सिंह की शास्त्री पर बढ़त	+34	+31

इनकार करने वाले शामिल नहीं

जाति

	ब्राह्मण	कायस्थ	ठाकुर	वैश्य	हरिजन	अन्य हिंदू	मुसलमान
वी.पी. सिंह	66	45	84	59	26	55	76
सुनील शास्त्री	31	49	13	35	15	27	17
कांशीराम	2	2	2	4	58	16	5
अन्य	1	4	1	2	1	2	2
वी.पी. सिंह की शास्त्री पर बढ़त	+35	−4	+71	+24	−11	+28	+59

इनकार करने वाले शामिल नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को बिलकुल धो डाला है. वैसे इन उत्तर-पूर्वी राज्यों में पार्टी को जीत भी उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार के एक लंबे सिलसिले के बाद ही हासिल हुई थी.

यहां तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस साल के शुरू में ही नए मुख्यमंत्री तैनात किए गए थे, ताकि पार्टी की छवि को सुधारा जा सके. राजस्थान में हरिदेव जोशी को वहां बढ़ रहे असंतोष और फिर रूपकंवर कांड या फिर सरिस्का प्रसंग के कारण हटा दिया गया, तो मध्यप्रदेश में भी इसी तरह भीतरी गुटबाजियों के कारण पार्टी को पहुंच रहे नुकसान को रोकने के लिए मोतीलाल वोरा की जगह अर्जुन सिंह को लाया गया. लेकिन इन दोनों राज्यों में हुए इन उपचुनावों में भी विपक्षी दलों को मिले साझे वोटों के मुकाबले सत्ताधारी दल को मिले वोटों में गिरावट आई है. इससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात तो यह है कि 1985 और दिसंबर 1987 के बीच हुए 22 लोकसभाई सीटों के उपचुनावों में इंका ने 19 सीटें जीती और केवल बिहार में एक तथा हरियाणा में दो स्थानों पर वह हारी थी. इसके मद्देनजर अब ताजा उप-चुनाव में पार्टी की करारी हार अशुभ संकेत ही मानी जाएगी.

यह सच है कि इस बार विपक्ष की एकता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लेकिन यह भी स्पष्ट है कि चुनाव परिणामों को राजीव सरकार के खिलाफ स्पष्ट फैसलों के रूप में गिना जा रहा है. इलाहाबाद में वी.पी. सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री और उनकी चौकड़ी को ही अपनी आलोचनाओं का मुख्य केंद्र बनाया. इंका के एक बड़े गढ़ में उनकी भारी जीत यह सिद्ध करती है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वे राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने लगे हैं. उधर इंका का सारा चुनाव अभियान भी राजीव और उनकी नीतियों पर आधारित रहा. यानी दोनों पक्षों ने एक ही मुद्दे को लक्ष्य बनाया. इसमें इंका की हार से अब यह स्पष्ट हो गया है कि राजीव का नाम अब वोट खींचने की ताकत काफी हद तक खो चुका है. यानी मिस्टर क्लीन में अब 'क्लीन स्वीप' करने (वोट बटोरने) का वह पुराना करिश्मा नहीं बचा है.

मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे संकेत देते हैं कि राजीव ने विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों को योग्य हाथों में सौंपने की कोशिश की है. कुछ को छोड़ दें तो अधिकांश नियुक्तियां बहुत बेमतलब नहीं लगतीं

इन सबसे कहीं ज्यादा हतोत्साहित करने वाली बात यह रही कि इंका ने इन उपचुनावों में 7 लोकसभा सीटों और 11 विधानसभा सीटो के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी. एक दर्जन से भी अधिक काबीना मंत्रियों को पूरे समय के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया गया था. यहां तक कि टीवी सीरियल रामायण के 'राम' अरुण गोविल और 'हनुमान' दारा सिंह का भी इलाहाबाद, उधमपुर और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया. लेकिन धार्मिक भावनाओं को उभारकर वोट जीतने की भोंडी कोशिशों से न तो पार्टी की छवि को बहुत लाभ पहुंचा और न ही उसका मकसद पूरा हुआ. कुछ महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों में मतदान में की गई हेराफेरी और मतदान केंद्रों पर कब्जे के प्रयास भी काम न आए.

इस चुनाव में इंका को हुआ नुकसान बहुत गंभीर है. उधमपुर में जहां 1987 में नेशनल कान्फ्रेंस और इंका के गठजोड़ ने 15 में से

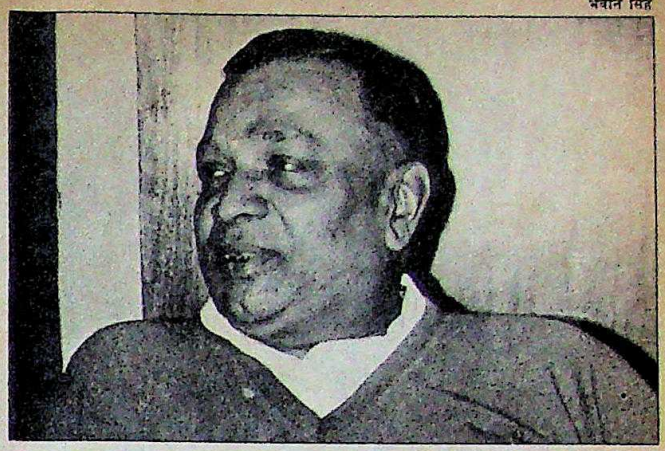

भवान सिंह

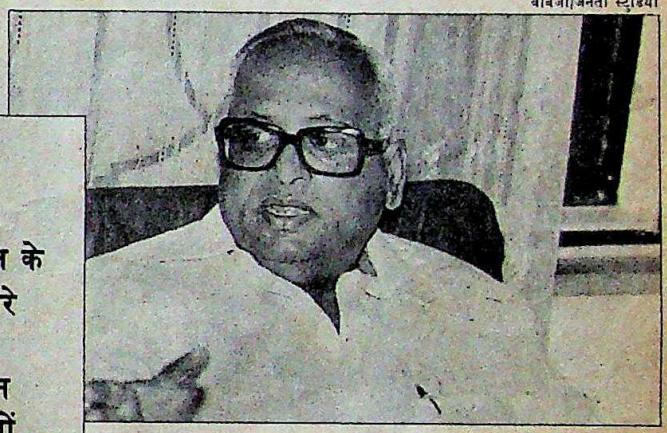

बाबजी/जनता स्टूडियो

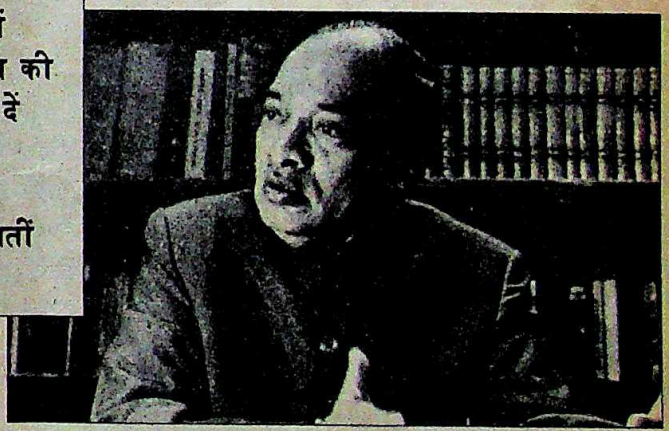

कृष्णमुरारी किशन

(ऊपर से) चव्हाण, वेंगलराव, नरसिंह राव और दुबे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमोद पुष्करणा

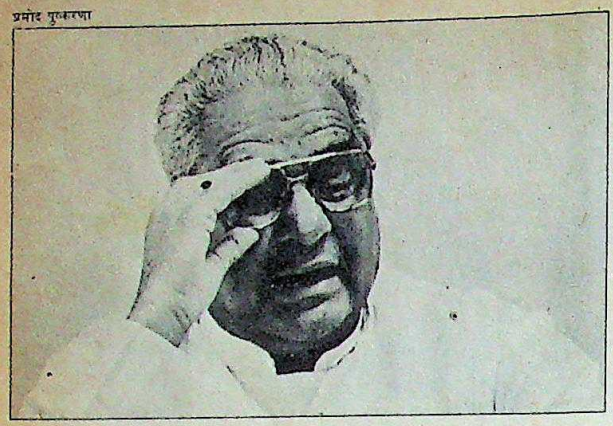

प्रमोद पुष्करणा

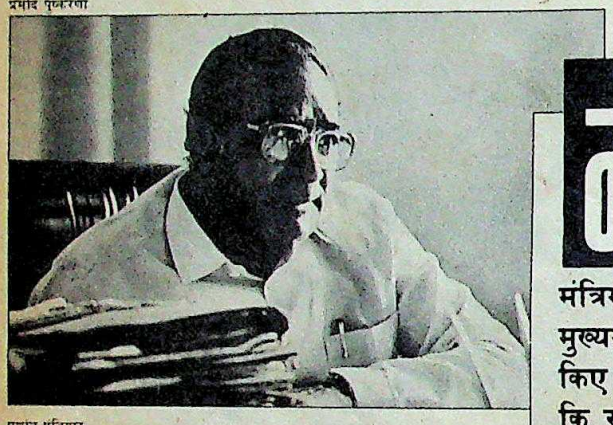

प्रशांत पंजियार

साबेत झावेरी

14 विधानसभा सीटें जीती थी, वहां इस बार इंका उम्मीदवार 12 में मात खा बैठा. मध्य प्रदेश में भी नए मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से मुश्किल से ही जीत पाए जहां से कांग्रेसी उम्मीदवार 1952 से लगातार जीतते चले आ रहे हैं. 1977 की जनता आंधी भी उसके इस गढ़ को नहीं तोड़ पाई थी. लेकिन इस बार भाजपा उम्मीदवार दिलीप सिंह जू देव ने अर्जुन सिंह को जबरदस्त टक्कर दी. मुख्यमंत्री किसी तरह जीत तो गए लेकिन इस चुनाव में हुए असामान्य 88 फीसदी मतदान ने भी उनकी जीत की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है.

चुनावों के बाद होने वाले विश्लेषणों ने तो इंका के लिए कुछ और अशुभ संकेत दिए हैं. उदाहरण के लिए इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इंका अपने परंपरागत वोट बैंकों—हरिजनों, आदिवासियों और मुसलमानों का समर्थन खो चुकी है. एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया, "1977 के चुनावों में भी हमने कमजोर वर्गों का समर्थन नहीं खोया था. लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोग यह मानने लगे हैं कि हमारी पार्टी अमीरों और ऊंची जातिवालों की पार्टी है."

नए मंत्रिमंडल में आठ पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किए जाने से साफ है कि राजीव गांधी पार्टी के किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते जो थोड़ा भी रसूख वाला हो

उधर सफलताओं ने विपक्ष के हौसले बढ़ा दिए हैं. आगामी आम चुनावों में अब वह राजीव और उनकी पार्टी के लिए कहीं अधिक गंभीर चुनौती बन चुका है. विपक्षी दलों को एक बार फिर यह एहसास तो हो ही गया है कि एकता रंग ला सकती है. लोग वैसे भी सरकार से असंतुष्ट हैं ही. जैसा कि जनता पार्टी के महासचिव हरिकेश बहादुर कहते हैं, "यह चुनाव राजीव गांधी और विपक्षी उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर थी. इंका उम्मीदवार राजीव के नाम पर वोट मांग रहे थे न कि पार्टी के नाम पर. इसलिए चुनावों का यह फैसला सीधे-सीधे राजीव के खिलाफ दिया गया फैसला है."

पर शायद राजीव के बजाय चुनाव में इस्तेमाल किए गए तरीके ही वे कारण बने जिनसे खुद राजीव की साख पर अचानक इस कदर बट्टा लगा है. राजीव द्वारा पार्टी और सरकार को अपनी व्यक्तिगत रियासत मानकर कामकाज चलाना भी निश्चित तौर पर पार्टी में असंतोष और फिर उसकी हार की एक प्रमुख कारण रहा है.

इंदिरा गांधी अगर मनमाने तरीके से कामकाज चला सकती थीं तो ऐसा करने की उनमें योग्यता भी थी. लेकिन जहां तक राजीव की बात है, उनमें न तो उतनी राजनैतिक सूझबूझ है और न पार्टी नेताओं पर उनका उतना नियंत्रण ही है.

उनको घेरे बैठे उनके दोस्त और युवा राजनेता न तो उनकी 'मि. क्लीन' वाली छवि बनाए रख पाए हैं और न ही पार्टी संगठन को इतना मजबूत कर पाए हैं कि वह विपक्ष का विश्वसनीय तरीके से मुकाबला कर सके. इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि आम जनता को लगने लगा है कि राजीव खुद अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं. 1985 और 1986 तक राजीव का रुतबा ऐसा था कि वे किसी भी अफसर या कनिष्ठ मंत्री को जहां चाहे भेज सकते थे या निकाल सकते थे या ऊंचा चढ़ा सकते थे लेकिन वह जमाना बीत चुका है.

(ऊपर से) भजनलाल, वोरा, बीरबहादुर और सोलंकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ठूंस कर राजीव ने इस राय को ही मजबूत किया है कि असफलताओं के बावजूद इनाम हासिल किए जा सकते हैं. पूर्व मुख्यमंत्रियों की लंबी फेहरिस्त गिनाते हुए भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुटकी ली, "केंद्रीय मंत्रिमंडल तो अब कूड़ेदान बन कर रह गया है."

सच तो यह है कि अधिकांश राजनैतिक प्रेक्षक भी इस फेरबदल को इस बात का प्रमाण मानने लगे हैं कि राजीव अब लगभग हर तबके को खुश करने की मजबूरियों में फंस चुके हैं. मुसलमानों को खुश करने के लिए जियाउर्रहमान अंसारी और रफीक आलम को तरक्की दे दी गई. लोकसभा में मुस्लिम महिला विधेयक की वकालत करने वाले अंसारी को काबीना मंत्री का दर्जा देकर राजीव ने एक तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने ही टेक दिए. बोफोर्स घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के अपने विश्वासपात्र अध्यक्ष बी. शंकरानंद को फिर से मंत्रिमंडल में लेकर उन्होंने दक्षिण के हरिजनों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया है.

पुराने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री थे जिनका कामकाज या तो प्रभावहीन था या फिर वे अपने पद और जिम्मेवारियों के योग्य ही नहीं थे. पर इसके बावजूद राजीव ने उनमें से किसी को भी हटाने का साहस नहीं दिखाया है. यहां तक कि जगदीश टाइटलर के मातहत एक नए ही फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के गठन को पेप्सी कोला को भारत में लाने के पक्षधरों की लॉबी की जीत माना जा रहा है.

रफीक आलम और जियाउर्रहमान अंसारी का दर्जा बढ़ा दिया गया. अंसारी ने मुस्लिम महिला विधेयक की लोकसभा में वकालत की थी. यानी राजीव एक तरह से कट्टरपंथियों के दबाव में आ गए

पर कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि राजीव अब वास्तविकता को स्वीकार करने या फिर उसी के साथ डूबने को तैयार हो गए हैं. इस संदर्भ में पवार और तिवारी के चयन को तुलनात्मक रूप से सही माना जा सकता है क्योंकि दोनों ही अपने-अपने राज्य में कुर्सी के बाकी दावेदारों से मुट्ठी भर ऊंचे ही माने जाते हैं. और वे प्रशासक भी अच्छे माने जाते हैं.

लेकिन काफी हद तक यह सब एक जुए जैसा भी है. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में फिलहाल किसी की कल्पना में भी यह नहीं था कि चव्हाण को हटाकर उनकी जगह पवार को गद्दी पर बिठा दिया जाएगा. पवार तो दावेदारों में भी नहीं थे. यह सब इतना अनपेक्षित था कि जिस समय 48 वर्षीय शरदचंद्र गोविंद पवार के नाम की घोषणा हुई, उस प्रदेश की राजनीति में रस्साकशी करने वाले अधिकांश लोग अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए बंबई में मौजूद नहीं थे. पद के तीन दावेदारों में से एक वसंतदादा पाटील अपने घर सांगली में थे. पवार गोवा में छुट्टियां मना रहे थे. वहां पार्टी में मची भीतरी कलह पर नियंत्रण पाने के लिए युवा पवार को ही उपयुक्त समझा गया. उनसे यह उम्मीद भी होगी कि आने वाले आम चुनाव में वे पार्टी की नैया किनारे लगा सकेंगे.

चव्हाण के लिए एक छोटा-सा मामला बहुत कठिनाई भरा सिद्ध हुआ. आलाकमान उनसे अपेक्षा कर रहा था कि वे बंबई क्षेत्रीय इंका कमेटी के नेताओं पर खुलेआम तीखा हमला करने वाली विवादास्पद शिक्षा राज्यमंत्री चंद्रिका केनिया को उनके पद से हटा देंगे. केनिया ने बंबई इंका कमेटी के दफ्तर को 'चोरों का अड्डा' और इसके सदस्यों को 'तस्कर' तक कहा था. जाहिर है इससे पार्टी का एक तबका बुरी तरह नाराज था. वास्तव में जब इंका महासचिव शीला कौल पार्टी में मुख्यमंत्री चव्हाण की ताकत का अंदाज लेने बंबई गई थीं तो केनिया को हटाने की मांग उनसे भी की गई थी. यहां तक कि बाद में राजीव ने स्थानीय इंका नेताओं, कुछ मंत्रियों और विधेयकों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी की जो केनिया की शिकायत लेकर आए थे. लेकिन चव्हाण केनिया की बरखास्तगी की मांग को अपना यह अनुरोध रख कर टालने में लगे थे कि पहले उन्हें अपने मंत्रिमंडल के विस्तार की अनुमति दी जाए.

यह जिद चव्हाण को महंगी तो पड़ी लेकिन केंद्र में उन्हें वित्तमंत्री बनाए जाने से उनकी प्रशासनिक योग्यताओं पर स्वीकृति का ठप्पा भी लग गया. और जब इस्तीफा देने के बाद चव्हाण अपनी पत्नी कुसुमताई के साथ पत्रकारों से मिले तो गर्व से उनका कहना था, "मैं

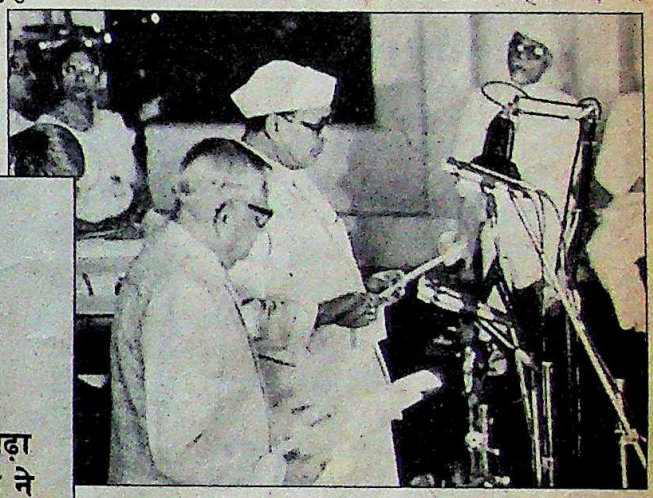

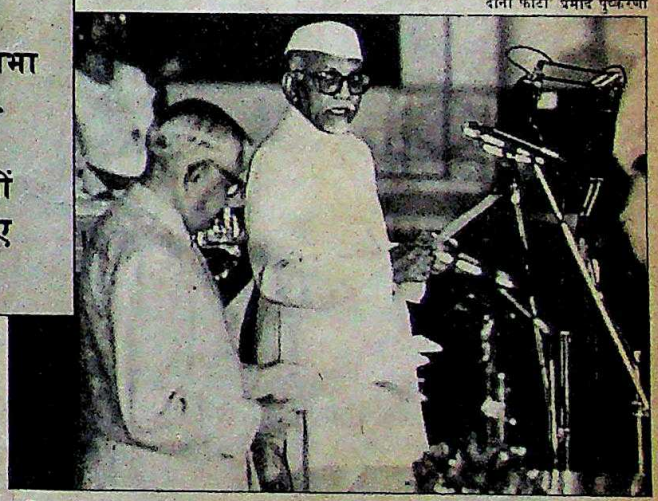

दोनों फोटो प्रमोद पुष्करणा

संतुष्टि की भावना से दिल्ली वापस जा रहा हूं."

अब यह पवार का सिरदर्द है कि वे उग्रपंथी हिंदू संगठन शिवसेना से निबटें और पार्टी की भीतरी कलह को शांत करके एकता स्थापित करें. उन्हें अच्छा प्रशासक होने के अलावा राजनैतिक सूझबूझ वाला और युवाओं तथा आम लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाला माना जाता है. औरंगाबाद के इंकाई सांसद साहिबराव दोणगांवकर, जहां हाल ही के नगरपालिका चुनावों में शिवसेना ने इंका को रौंद दिया था, कहते हैं, "इसमें शक नहीं पवार के हाथ में बागडोर आ जाने से शिवसेना पर अंकुश लगाया जा सकेगा."

हालांकि यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पवार को वसंतदाता पाटील के समर्थकों के गुट से विरोध का सामना करना पड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विपक्ष: नेतृत्व का प्रश्न

कोई सूरत उन्हें नहीं भाती

विपक्षी नेताओं के मतभेदों के मूल में है एक ऐसे नेता की तलाश जो अगले आम चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व कर सके. हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल को छोड़कर कोई भी बडा नेता या दल वी.पी. सिंह के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया है. हालांकि चंद्रशेखर से लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव तक सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने गए पर उनमें से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि वी.पी. सिंह में वोट बटोरने की क्षमता उन सभी से अधिक है. लेकिन वे यह भी मानते हैं कि इंका को मात देना तब तक संभव नहीं है जब तक संयुक्त विपक्ष के पास कोई विश्वसनीय और पाक-साफ छवि वाला नेता न हो. भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं, "किसी एक नेता के बिना चुनाव लड़ने से विपक्ष

सतही तौर पर तो लगता है कि इलाहाबाद उपचुनाव में इंका के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह को साझा उम्मीदवार बनाकर विपक्षी नेताओं ने साबित कर दिया कि वे अब समझदार हो गए हैं. विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए माकपा से लेकर भाजपा तक ने इलाहाबाद में खूंटा गाड़ दिया था. लेकिन थोड़ी गहराई में जाकर देखें तो यह एकता का एक छिछला दिखावा भर ही साबित होगा. आज फिर ढाक के तीन पात वाली स्थिति है.

और यह स्थिति एक तरह से कुछ बातों की तार्किक परिणति ही लगती है. जैसे-जैसे यह संभावना प्रबल होती दिख रही है कि संगठित विपक्ष इंका को पछाड़ सकता है, विपक्ष के नेतृत्व के लिए दावेदारी बढ़ती जा रही है. आज जबकि विपक्षी नेताओं को उपचुनावों में मिली सफलता को और मजबूती प्रदान करने के लिए सोच-विचार करना चाहिए था, वे नेतृत्व की दावेदारी तय करने की चिंता में दोहरे होते जा रहे हैं.

इस चिंता से दोहरे होने यानी विपक्षी नेताओं में पहले ही की तरह अहं की टकराहट बरकरार होने का पहला संकेत जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर के सिवा भला और कौन दे सकता था? अपनी पार्टी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए उन्होंने आज उसे जर्जर हालत में पहुंचा दिया है. साफ है कि अभी भी चंद्रशेखर की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही एकटक लगी हुई है.

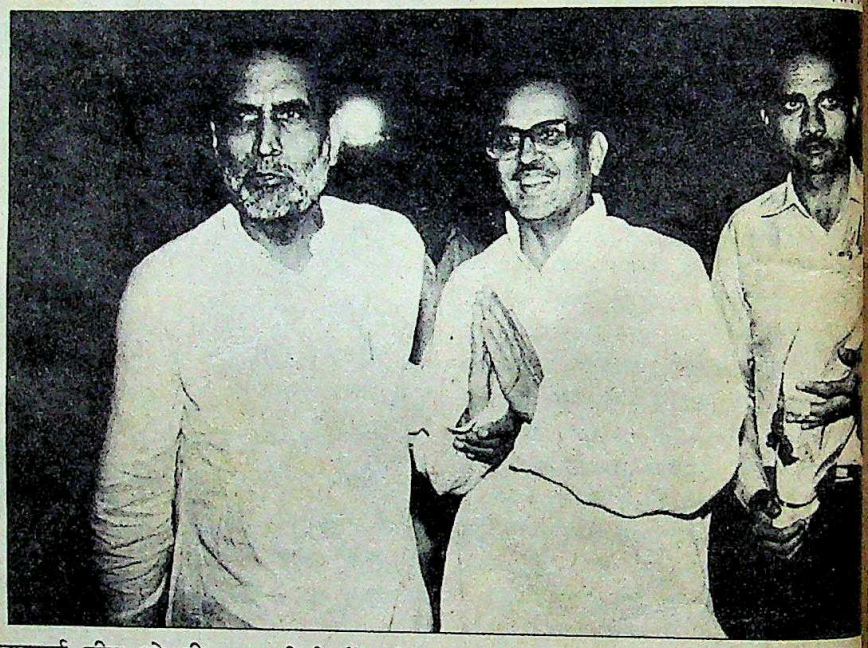

वी.पी. सिंह के साथ चंद्रशेखर (बाएं): अहं की टकराहट

इलाहाबाद के नतीजे आने के बाद चंद्रशेखर ने न सिर्फ वी.पी. सिंह की महत्वपूर्ण जीत को ही नजरअंदाज करने की कोशिश की बल्कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें भावी प्रधानमंत्री माने जाने की भी खिल्ली उड़ाई. चंद्रशेखर ने पुणे में कहा, "वी.पी. सिंह इस हद तक तवज्जो के हकदार नहीं हैं. हम राजीव गांधी का विकल्प चाहते हैं न कि उन्हीं जैसा कोई व्यक्ति. मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अखबारवालों द्वारा बनाए हुए नेताओं के सम्मोहन में बिना सोचे-समझे ही बह जाते हैं."

दरअसल वी.पी. सिंह के खिलाफ चंद्रशेखर के इस कदर फूट पड़ने से उत्तर भारत में विपक्ष की कुछ महत्वपूर्ण जीतों से बना उत्साह कुछ हद तक ठंडा पड़ गया. इन महत्वपूर्ण जीतों में इंका से छीनी गई चार लोकसभाई सीटें भी शामिल हैं. महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि लोकसभा की सात में से छह और विधानसभा की 11 में से 10 सीटों पर विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा कर सका. और यदि राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में इंका जीत पाई तो उसका एकमात्र कारण यही था कि इन दोनों क्षेत्रों में लोकदल ने भी भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले अपने प्रत्याशी खड़े किए थे. लोकदल के ये दोनों ही उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे.

की छवि पर भारी असर पड़ेगा. अब कोई जयप्रकाश नारायण तो हैं नहीं कि पार्टी पर किसी नेता को थोप सकें."

वैसे दूसरे नेताओं द्वारा न स्वीकारे जाने की कुछ हद तक जिम्मेदारी खुद वी.पी. सिंह पर भी आती है. दो हफ्ते तक वे उत्तर प्रदेश से ही बाहर नहीं निकले, और न ही उन्होंने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का ही कोई प्रयास किया. इस तरह विपक्षी दलों में अपने कई साथियों को उन्होंने निराश ही किया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े कहते हैं, "इलाहाबाद ने वी.पी. सिंह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है जो विपक्षी दलों को एक मंच पर ला सकता है. आज जनमत उनके साथ जो है!" लेकिन वी.पी. सिंह कहते हैं, "मैं तभी कोई पहल करूंगा जब वे मुद्दों और कार्यक्रमों पर एक साथ आने को तैयार होंगे. वैसे इन उपचुनावों के बाद विपक्षी एका की संभावना निश्चित रूप से मजबूत हुई है."

वी.पी. सिंह को नेता के रूप में न स्वीकारे जाने के पीछे एक बड़ा कारण राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में उनका अस्पष्ट रवैया भी है. इंका से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हटने के साल भर बाद भी वे भ्रष्टाचार और कुछ छोटे-मोटे मुद्दों की ही बात कर रहे हैं. वे पंजाब, सांप्रदायिकता, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साधे रहे हैं. उन्होंने किसी विचारधारा को नहीं अपनाया है इसलिए कम्युनिस्ट भी उनसे दूर हैं. वे उनका समर्थन तो करना चाहते हैं पर तभी जब सिंह भाजपा को ठुकरा दें.

उधर वी.पी. सिंह को अपने ही जनमोर्चे में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इलाहाबाद उपचुनाव के दौरान जनमोर्चा में असंतोष भड़क उठा. इसके संयोजक रामधन और प्रमुख नेता आरिफ मुहम्मद खां ने चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों को शामिल करने पर आपत्ति उठाई.

लेकिन आंतरिक मतभेद केवल जनमोर्चा में ही नहीं भड़के. और नेता पर आम सहमति का मुद्दा और जटिल हो गया. वी.पी. सिंह के खिलाफ चंद्रशेखर की नाराजगी का एक कारण यह भी है कि उनके कट्टर दुश्मन हेगड़े खुलकर उनके पक्ष में हैं. लोकदल के अध्यक्ष हेमवतीनंदन बहुगुणा वी.पी. सिंह को विपक्ष का नेतृत्व सौंपने का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि देवीलाल जनमोर्चा नेता का डंका पीट रहे हैं. उधर गेरुआ वस्त्रधारी रामराव नेतृत्व के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं. उन्हें उम्मीद है कि उत्तर भारत के विपक्षी दल एकमत न हुए तो अंततः नेता वही बन सकते हैं.

दूसरी तरफ सभी दल हर राज्य में अपना जनाधार फैलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं ताकि चुनाव के समय वे अपने लिए ज्यादा सीटों का दावा कर सकें. यही कारण है कि हरियाणा सरकार की दो साझीदार पार्टियां लोकदल और भाजपा राजस्थान में एक-दूसरे से भिड़ गईं. और दोनों ही मात खा गईं.

लेकिन कम-से-कम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महसूस करते हैं कि मतभेदों का निबटारा बहुत ही जरूरी है. जनमोर्चा के नेता अरुण नेहरू ने कहा, "हर किसी को साथ आना होगा. लोग एक विश्वसनीय विपक्ष चाहते हैं. एका की पहल को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करने वाला राजनीति से साफ हो जाएगा."

एकता की अवधारणा भी हर विपक्षी नेता की अलग-अलग है. अजीत सिंह और चंद्रशेखर के नेतृत्व वाला गुट लोकदल का जनता पार्टी में विलय कराकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने के पक्ष में है. लेकिन हेगड़े की तरह कुछ नेता भाजपा समेत सभी पार्टियों का एक साझा राष्ट्रीय मंच चाहते हैं जिसमें सभी पार्टियों का अलग-अलग अस्तित्व बरकरार रहे और सीटों पर तालमेल किया जाए. रामराव सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक संघीय पार्टी बनाने की वकालत करते हैं. उनके फार्मूले के तहत सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव तो एक झंडे और एक चुनाव चिन्ह से लड़ेंगी पर विधानसभा के चुनाव में वे अपने चुनाव चिन्ह कायम रखेंगी. राज्यसभा में तेलुगु देशम के नेता पी. उपेंद्र कहते हैं, "यह फार्मूला सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए सबसे उपयुक्त है." मतदाता पर इसका असर भी पड़ेगा.

यहां तक कि 1977 के जनता प्रयोग की असफलता के बाद मध्यम दर्जे के विपक्षी नेताओं का भी मानना है कि सबसे पहले किसी एक नेता पर सहमति होनी चाहिए जिसे राजीव के विकल्प के रूप में खड़ा किया जा सके. वी.पी. सिंह इसके लिए तर्कसम्मत उम्मीदवार हो सकते हैं पर दूसरे विपक्षी नेताओं का जो रवैया है उससे तो यही लगता है कि वे चुनाव में हार जाना तो मंजूर करेंगे लेकिन उन्हें नेता मानना मंजूर नहीं करेंगे. —प्रभु चावला

सकता है लेकिन इंका विधायक दल की कार्यवाहियों में अनमने ढंग से शरीक पाटील का कहना था कि पवार के आने से पार्टी में गुटबंदी खत्म होगी. नए मुख्यमंत्री को बंबई इंका अध्यक्ष मुरली देवड़ा से भी जोरदार समर्थन मिला है. देवड़ा चव्हाण विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. इसलिए चव्हाण की छुट्टी से उनकी यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही मानी जाएगी. उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि पवार राज्य को अच्छा नेतृत्व देंगे, "वे युवा हैं, योग्य हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं और अलगाववादी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं."

लगभग ऐसे ही कुछ कारणों से नारायणदत्त तिवारी को भी केंद्र से हटाकर उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला किया गया है. उन्हें उनके प्रशासनिक गुणों और राज्य में अच्छे रसूख के लिए जाना जाता है. पर इस पद पर वे पहले भी कई बार रह चुके हैं. 1976 में उन्हें हेमवतीनंदन बहुगुणा की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था. लेकिन 1977 में जनता पार्टी की आंधी में वे बुरी तरह उखड़ गए थे. अगस्त 1984 में श्रीमती गांधी ने उन्हें फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और तब तत्कालीन प्रदेश इंका अध्यक्ष वी.पी. सिंह के सहयोग से वे संसद और विधानसभा की सीटों पर जीते थे.

लेकिन इस बार वे राज्य के उथलपुथल भरे वातावरण में वापस जाने को बहुत तैयार नहीं थे. यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इस बार उन्हें न केवल हमलावर रुख अपनाए हुए वी.पी. सिंह का मुकाबला करना है बल्कि पार्टी के जर्जर ढांचे को भी दुरुस्त करना है. मुख्यमंत्री के एक करीबी विधायक की व्यंग्य भरी टिप्पणी थी, "झिझकते हुए घोड़े से रेस जीतने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए." लेकिन मौजूदा हालात में तिवारी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है.

लेकिन महत्वपूर्ण होते हुए भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र केवल दो ही राज्य तो हैं. बाकी इंका शासित राज्यों में भी राजीव के पास बहुत सीमित विकल्प हैं. गुजरात में अमर सिंह चौधरी और ओडीसा में जे.बी. पटनायक का कोई विकल्प नहीं दिख रहा. राजस्थान में हाल ही में बनाए गए मुख्यमंत्री और प्रदेश इंका अध्यक्ष को भी अभी अपनी योग्यताएं सिद्ध करनी हैं. उधर बिहार में भागवत झा आजाद ने अभी से स्पष्ट संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वे पार्टी में विभिन्न गुटों के दबाव में फंस चुके हैं.

पार्टी के लिए हताश करने वाली बात यह है कि वह निचले स्तर पर एकदम पंगु होकर रह गई है. इंका महासमिति में नौ बार फेरबदल के बावजूद पार्टी आलाकमान निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में असफल रहा क्योंकि दिल्ली से थोपे गए नेता उन्हें प्रभावित नहीं कर पाए. राज्यों में पार्टी का नेतृत्व युवा लोगों के हाथों में सौंपने का प्रयोग भी लगभग असफल रहा है.

कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राजीव उन पुराने अनुभवी नेताओं की शरण में लौट रहे हैं जिनकी छवि नव धनाढ्यों, समाज के ग्लेमर-पुते चेहरों की छवि के मुकाबले कांग्रेस की परंपरागत छवि से कहीं अधिक मेल खाती है. लेकिन पुरानी पीढ़ी की ओर यह वापसी भी आधी-अधूरी और देरी से हुई दिखती है.

राजीव के सामने अब असली संकट यह है कि उनके पास समय बहुत कम बचा है. हर फैसला अब 5, रेसकोर्स के दरवाजे पर आकर इंतजार करने लगा है. उधर विपक्ष की नीति स्पष्ट है—सरकार और सीधे राजीव के खिलाफ अभियान चलाना. आने वाले महीनों में बोफोर्स कांड के भयानक शक्ल लेने के खतरे को देखते हुए लगता है कि राजीव पर मुश्किलों का कहर टूटने जा रहा है. इन मुश्किलों से निबटते हुए उन्हें इस राजनैतिक सचाई से दो-चार होना पड़ सकता है कि विश्वसनीयता जितनी घटती है, मुश्किलें उसी अनुपात में बढ़ती जाती हैं.

—प्रभु चावला और दिलीप बॉब के साथ
एम. रहमान बंबई में और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बोफोर्स घोटाला

लाजवाब कर देने वाले तथ्य

'द हिंदू' के नए रहस्योद्घाटनों ने सरकारी दावों की पोल खोली

अब से कुछ साल पहले तक तो भारत सरकार इस्लामी बम को लेकर चिंतित था. अब वह 'द हिंदू बम' की वजह से परेशान है. मद्रास का यह अखबार पिछले कई महीनों से बोफोर्स घोटाले पर एक के बाद एक धमाके कर रहा है. उसने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित किए हैं. जब लगा कि विवाद ठंडा पड़ गया है और सरकार यह साबित करने में कामयाब हो रही है कि 1986 में हुए तोप सौदे में कोई घपला नहीं किया गया, तभी पिछले पखवाड़े अखबार ने रहस्योद्घाटनों का दूसरा दौर शुरू कर दिया. और सरकारी दावों की कलई खुल गई.

अखबार ने ऐसे कई दस्तावेज छापे जिनसे पता लगता है कि बोफोर्स द्वारा तोप सौदे में दलालों को दलाली दी गई थी, न कि 'करार समेटने के रूप में भुगतान' किया गया था. इसके पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को यही बताया गया और उसने इस तर्क को स्वीकार भी कर लिया था कि भारत सरकार के अनुरोध पर दलालों की छुट्टी करने के एवज में उन्हें भुगतान किया गया था. इससे बड़ा रहस्योद्घाटन इस अखबार ने यह किया कि ये भुगतान या तो भारतीयों को हुआ अथवा उनके जरिये हुआ. इस तरह जेपीसी और सरकार के दावे ध्वस्त हो गए कि इस सौदे में दलाली नहीं दी गई.

रहस्योद्घाटनों के बाद सरकार तुरंत सक्रिय हो गई. पिछले पखवाड़े जैसे ही दस्तावेजों की पहली खेप छपी, कुछ ही घंटों के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की. इस बैठक में रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत, रक्षा सचिव टी.एन. शेषन, केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक मोहन कात्रे, प्रवर्तन निदेशक अनिल कुमार, सरकारी प्रवक्ता जी.के. अरोड़ा और प्रधानमंत्री सचिवालय के दो संयुक्त सचिव शरीक हुए.

जल्दी ही फैसला ले लिया गया कि इस रहस्योद्घाटन के मद्देनजर अब मामले की नए सिरे से जांच-पड़ताल शुरू की जाए. लेकिन 'द हिंदू' ने आगे भी और जो दस्तावेज छापे उनसे यही साबित हुआ कि बोफोर्स ने भारतीय सौदे में दलाली दी थी, और यह कि पिछले साल से बोफोर्स 'करार समेटने' की जो रट लगाता रहा है वह दरअसल पुराने दस्तावेजों पर पुरानी तारीख डालकर मामले की लीपापोती की कोशिश ही थी. ताजा प्रकाशित दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो द्वारा किए गए भंडाफोड़ के ठीक पहले तक दलाली

ताजा रहस्योद्घाटनों के दो दिनों के भीतर ही विन चड्ढा को कर संबंधी नोटिस थमा दिए गए और उनके देश छोड़ कर जाने पर भी रोक लगा दी गई

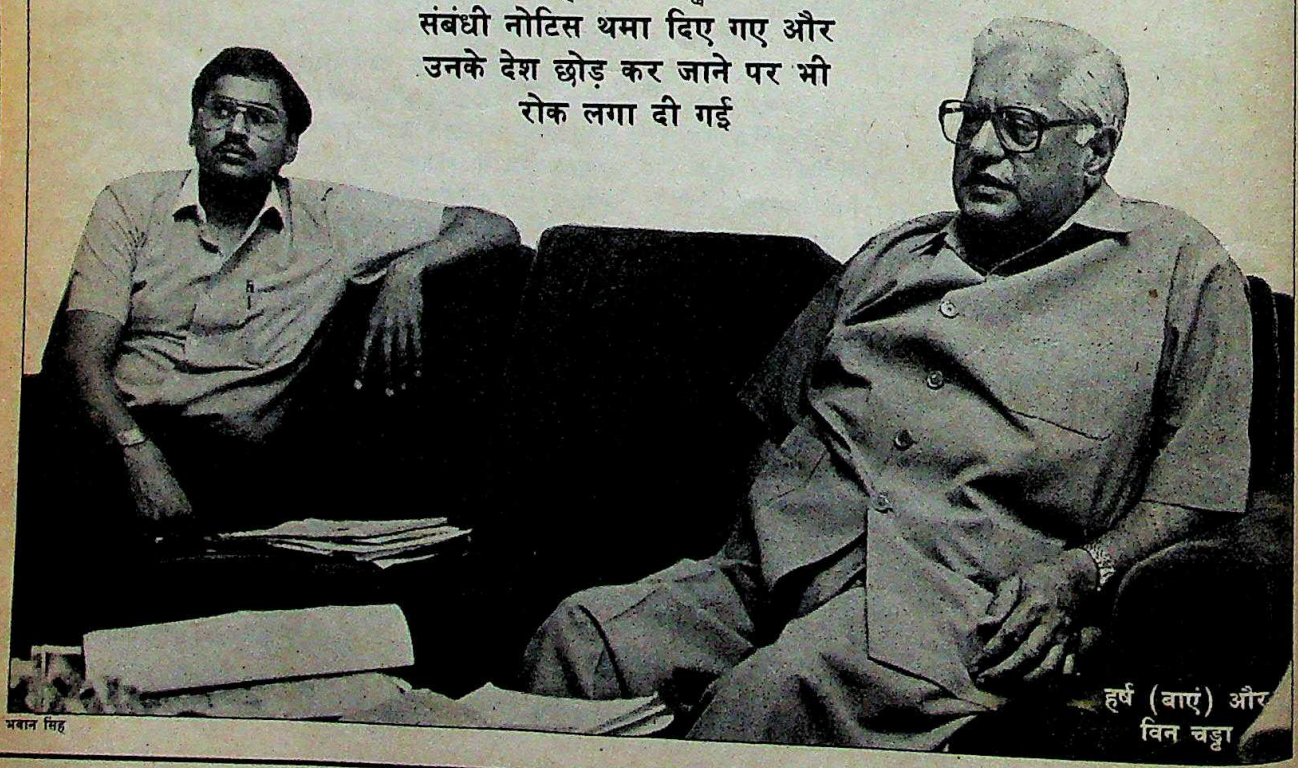

भवान सिंह

हर्ष (बाएं) और विन चड्ढा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का भुगतान किया जाता रहा है.

इन नए रहस्योद्घाटनों से लोगों को कोई संदेह नहीं रह गया है कि जेपीसी और सरकार के निष्कर्ष सही नहीं थे. भले ही इसकी वजह मामले को रफादफा करने की कोशिश रही हो अथवा जांच-पड़ताल में हुई बेहद लापरवाही. शर्म से लाल अधिकारी पिछले पखवाड़े इस बात की तरह-तरह से सफाई देते रहे कि क्यों एक अखबार और जेनेवा में उसकी एकमात्र संवाददाता वे तमाम सबूत जुटाने में कामयाब रहीं जिन्हें सरकार अपनी तमाम सुविधाओं, साधनों और अधिकारों के बावजूद निकाल नहीं पाई.

लेकिन इन नए तथ्यों ने एक शख्स को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है. और वे हैं भारत में बोफोर्स के भारी-भरकम प्रशासनिक सलाहकार विश्वेश्वर नाथ (विन) चड्ढा. 'द हिंदू' द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों के बारे में इसके सह-संपादक एन.राम का कहना था कि 1,700 करोड़ रु. के भारतीय सौदे में 64 करोड़ रु. की दलाली पाने वाले तीन दलालों में से एक, पनामा की स्वेंस्का और चड्ढा की एनाट्रॉनिक जेनरल कार्पोरेशन के बीच "नजदीकी रिश्ता" था. अखबार ने दिखाया कि बोफोर्स ने 1978 से स्वेंस्का और एनाट्रॉनिक के साथ अमूमन एक ही वक्त करार किए. इसके अलावा स्वेंस्का के करार में चड्ढा का उल्लेख भी है. दरअसल, स्वेंस्का के करार के मुताबिक एनाट्रॉनिक अगर बोफोर्स के साथ अपने करार को नहीं निभा पाई तो स्वेंस्का को भुगतान नहीं किया जाएगा. इस शर्त से दोनों में आपसी संबंध होने का संकेत मिलता है. एक और तथ्य से दोनों के 'आपसी संबंध' होने की बात उजागर होती है. बोफोर्स ने दोनों कंपनियों को दूसरी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी थी. और दोनों कंपनियों की दी गई यह सूची समान है.

इंडिया टुडे से मुलाकात में चड्ढा ने 'द हिंदू' के आरोपों के लंबे-चौड़े जवाब दिए और इस बात पर जोर दिया कि स्वेंस्का से उनका कोई लेना-देना नहीं. अखबार में छपे दस्तावेजों की खामियां बताते हुए (देखें बातचीत) उन्होंने दृढ़ता से कहा, "मेरा धंधा एकदम पाक-साफ है. मैं दूसरे दलालों की तरह नहीं हूं."

हिंदुजा घराने के चार में से एक भाई गोपीचंद हिंदुजा भी, जो लंदन में बसे हैं, शक के घेरे में हैं. पिछले अप्रैल में किए गए रहस्योद्घाटनों में 'द हिंदू' ने बोफोर्स द्वारा किए गए भुगतान की एक किस्त के साथ हिंदुजा को भी जोड़ा था. और इस बार अखबार ने उस पत्र की प्रति छापी है जो हिंदुजा ने 5 फरवरी 1987 को बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो और उपाध्यक्ष हांस एक्ब्लोम को लिखा था. इस खत से पता चलता है कि ये तीनों अभी हाल में मिले थे. अखबार ने इस मसले पर आर्डबो की डायरियों का हवाला भी दिया है जिनके मुताबिक 30 जनवरी को वे लंदन में किसी 'एच' से मिले. डायरी में (जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है) किसी 'जीपीएच' का भी उल्लेख है. इन उल्लेखों से इस मामले में हिंदुजा के किसी न किसी रूप में शामिल होने की पुष्टि होती है.

'द हिंदू' ने उस पत्र की प्रति भी छापी है, जो हिंदुजा ने बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष आर्डबो को लिखा था. आर्डबो की एक डायरी का भी हवाला दिया गया है जिसके अनुसार उन्होंने लंदन में किसी 'एच' से भेंट की थी

इस बीच सरकार भी हरकत में आ गई. 'द हिंदू' द्वारा भंडाफोड़ के पहले दौर से तो (जिसमें हिंदुजा के शामिल होने की बात उजागर हुई थी) अधिकारी उदासीन बने रहे क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिखता था. लेकिन इस बार उन्होंने अस्वाभाविक तेजी दिखाई.

अधिकारियों ने कबूल किया है कि चड्ढा और स्वेंस्का के बीच संबंध होने के पर्याप्त कारण' हैं और स्वेंस्का को किया गया भुगतान (कम से कम 18.84 करोड़ क्रोनर या 37.7 करोड़ रु.) संभव है चड्ढा के लिए ही हो. अधिकारियों का कहना था कि वे इस मामले की छानबीन प्रवर्तन आयकर और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन और आय को छिपाने के सदर्भ में कर सकते हैं. जांच-पड़ताल कर रही एक एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था, "हमारा ख्याल है कि कर चोरी का नजरिया अपनाना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इस आरोप को साबित करने के लिए भुगतान की जांच-पड़ताल में स्विस अधिकारियों की मदद जरूरत पड़ने पर मिल सकती है. वे हमारे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले पर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे."

इसका नतीजा यह निकला कि द हिंदू द्वारा रहस्योद्घाटन के दो दिनों के भीतर ही चड्ढा को कर संबंधी नोटिस थमा दिए गए. सावधानी के बतौर उनके देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी गई. उनसे जल्दी ही प्रारंभिक पूछताछ की जाएगी और आगे भी पूछताछ के कई दौर चलेंगे.

अधिकारियों का कहना है कि यदि चड्ढा के खिलाफ कर नियमों के उल्लंघन का मामला (तीन या चार हफ्तों में) साबित हो गया तो स्विस अधिकारियों से अनुरोध किया जाएगा कि जिन खातों में बोफोर्स ने भुगतान किया था वे उनकी जानकारी दें. इस बीच 'द हिंदू' के आरोपों पर बोफोर्स की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसे खत भेज दिए गए.

इनके अलावा द हिंदू ने दो और ठोस सबूत छापे जिनसे सिद्ध होता है कि बोफोर्स ने सरकार से झूठ बोला कि भुगतान करार समेटने के लिए किए गए. पहले तो बोफोर्स ने कहा था कि 1986 में ही करार समेटने के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया. लेकिन 'द हिंदू' ने जो भुगतान संबंधी दस्तावेज छापे हैं वे मार्च 1987 के हैं. दूसरी बात यह कि बोफोर्स ने जनवरी 1986 में स्वेंस्का के साथ करार किया था जिसमें मार्च 1986 में भारत सरकार के साथ होने वाले करार का जिक्र है. इससे साफ जाहिर है कि दस्तावेज में हेरफेर कर पुरानी तारीखें डाल दी गईं.

'द हिंदू' के सह-संपादक एन. राम ने इंडिया टुडे को बताया कि स्वीडिश दस्तावेजों के अनुसार स्वेंस्का और एनाट्रॉनिक के साथ करार समेटने के किसी समझौते का जिक्र नहीं है. तीसरी कंपनी के मामले में राम का कहना था कि पिछले साल अप्रैल में स्वीडिश रेडियो द्वारा रहस्योद्घाटन किए जाने के बाद उसके साथ करार रद्द करने का समझौता किया गया होगा.

इस बात की पूरी संभावना है कि अगले कुछ हफ्तों में अखबार फिर कुछ नए धमाके करेगा. और तब किसी निष्कर्ष के आसपास पहुंचा जा सकेगा. सूचनाओं के मुताबिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विन चड्ढा

"जाली दस्तावेजों से दोषी कैसे ठहराएंगे?"

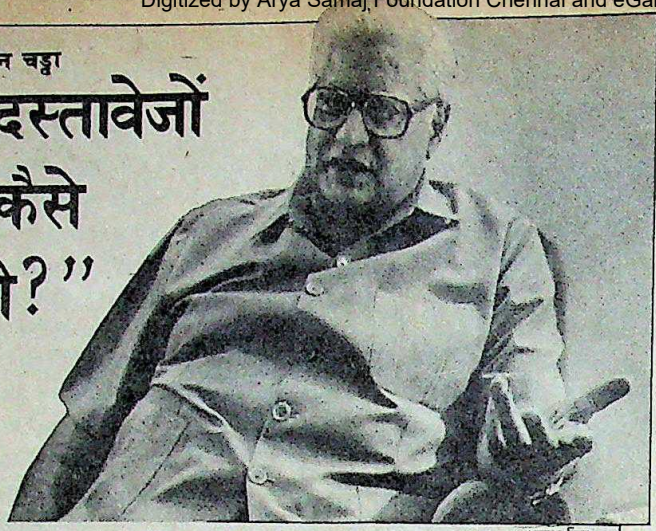

भवान सिंह

हालांकि 'द हिंदू' में छपे दस्तावेजों से बोफोर्स द्वारा किए गए भुगतानों में विन चड्ढा की भागीदारी साफ जाहिर हो जाती है, लेकिन वे इसी बात पर अड़े हैं कि उनका धंधा 'बिलकुल साफ-सुथरा' था. उनसे बातचीत के अंश:

● संयुक्त संसदीय समिति के सामने आपने कहा था कि आप बोफोर्स की ओर से कभी किसी सरकारी अधिकारी से नहीं मिले. लेकिन 'द हिंदू' ने 1978 में बोफोर्स के साथ हुए आपके करार का जो दस्तावेज छापा है उसके अनुसार आपका काम यह पता लगाना भी था कि कौन-सा सुरक्षा अधिकारी ज्यादा प्रभावशाली है.

मेरे पास 1978 वाले समझौते की कॉपी नहीं है, 1981 में हुए समझौते में, जो कि उसकी नकल ही था, वे दो धाराएं नहीं हैं जो 'द हिंदू' ने छापी है. और फिर, संसदीय समिति के सामने मैं तोप सौदों की जानकारी देने गया था. 1978 का समझौता सौदे से पहले हुआ था. पर अधिकारी से संबंधित शर्त में बुराई क्या है?

● 'द हिंदू' का कहना है कि बोफोर्स ने आपसे और पनामा की स्वेंस्का से जो समझौते किए उनमें काफी समानताएं हैं. तारीखों, भाषा और उन कंपनियों के, जिनका कि आप और स्वेंस्का प्रतिनिधित्व करते हैं, संदर्भ में गहरा साम्य है. इसका यह मतलब हुआ कि स्वेंस्का भी आप ही की कंपनी है.

मैं नहीं जानता कि स्वेंस्का क्या बला है. बोफोर्स तो सभी समझौतों में एक-सी भाषा ही इस्तेमाल करता है. जहां तक तारीखों का सवाल है, उनमें छह महीने तक का अंतर है. मैंने बोफोर्स के साथ 1981 और 1982 में समझौते किए थे. जिन्हें 'हिंदू' ने नहीं छापा है. और इसने दो ऐसी कंपनियों का भी हवाला दिया है, जिनमें से एक का प्रतिनिधित्व मैंने कभी नहीं किया, और दूसरे का उस खास समय में मैं प्रतिनिधि नहीं था.

● लेकिन स्वेंस्का-बोफोर्स करार कहता है कि यदि आप इस करार का सम्मान नहीं करते तो स्वेंस्का को भुगतान नहीं किया जाएगा. इससे दोनों के संबंधों की पुष्टि ही होती है.

हिंदू में प्रकाशित 1986 के समझौते के दस्तावेज पर जनवरी की तारीख पड़ी है. इसमें मार्च '86 में हुए एक करार का उल्लेख है. यह जाली दस्तावेज लगता है. फिर इसकी वैधता क्या है? जाली दस्तावेजों के आधार पर आप मुझे दोषी कैसे ठहराएंगे. इस करार के अनुसार स्वेंस्का मेरे जरिये बिक्री से बोफोर्स की मदद कर सकती है. लेकिन बोफोर्स के साथ हुए मेरे करार में कहा गया है कि मैं बिक्री में मदद नहीं करूंगा.

● यदि स्वेंस्का का संबंध आपसे कोई नहीं है तो क्या वह इस शर्त को मानेगी?

यह मैं कैसे बता सकता हूं? वे पनामा के लातिनीभाषी लोग हैं. हो सकता है, उन्होंने करार की अंग्रेजी भाषा समझे बिना ही दस्तखत कर दिए हों.

● क्या आप यह मानते हैं कि यह भुगतान दलाली अथवा करार समेटने के लिए किया गया?

यह तो व्याख्या और आपसी समझदारी पर निर्भर करता है.

● क्या आपको लगता है कि सरकार आपको बलि का बकरा बनाएगी?

मैं यह होने नहीं दूंगा.

इसके पास बोफोर्स के 100 पेजी दस्तावेज हैं जिनमें से पिछले पखवाड़े तक इसने तकरीबन 60 प्रकाशित कर दिए हैं.

अब इसमें कोई शक नहीं कि अखबार और इसकी जेनेवा संवाददाता चित्रा सुब्रमण्यम ने किसी 'पहुंचे हुए शख्स' से गहरी मित्रता गांठ ली है जो अंतिम सचाई को उजागर करने के लिए जरूरी सभी दस्तावेज उपलब्ध करा सकता है. पिछले पखवाड़े यह पूछने पर कि क्या अखबार किसी सोची-समझी रणनीति के तहत ये रहस्योद्घाटन कर रहा है तो राम का जवाब था कि उपलब्ध "हमें जो भी सूचना मिली है उसे प्रकाशित कर दिया गया है."

इस दौरान सरकारी अधिकारी छोटे-छोटे अक्षरों में छपे इन दस्तावेजों की पूरी इबारत पढ़ने की कोशिश में लगे रहे. जांच-पड़ताल से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि वे अखबार में छपी सभी बातों पर पहली ही नजर में विश्वास करने को तैयार नहीं हैं. इससे लगता है कि आधिकारिक जांच-पड़ताल नए सिरे से शुरू हो सकती है. लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार क्या इस बार वे कोई ठोस सबूत हासिल कर पाएंगे? राम कहते हैं, "अपने पुराने क्रियाकलापों के मद्देनजर उन्हें यह साबित करना है कि वे इस मसले पर अब सचमुच गंभीर हैं."

सरकारी पड़तालियों की दलील थी कि उन्हें मामले को आगे बढ़ाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. राम ने एक सलाह दी है कि स्वीडन के सरकारी वकील लार्स रिंगबर्ग सूचनाओं के अच्छे स्रोत साबित हो सकते हैं. लेकिन शायद रिंगबर्ग कोई मदद न कर पाएं क्योंकि उन्होंने अपनी जांच-पड़ताल समाप्त कर दी है. भारतीय कानून के तहत सीबीआई किसी ऐसे मामले से संबंधित कागजात किसी को नहीं दे सकता जिसकी जांच-पड़ताल समाप्त कर दी गई हो.

इस मामले में एक और दिक्कत आड़े आती है. वह यह कि सरकार को विदेशी सरकारों के सहयोग पर ही आश्रित रहना पड़ेगा. एक वरिष्ठ जांच अधिकारी का कहना था, "हम पत्रकारों सरीखे नहीं हो सकते. हमें तो सरकारी प्रक्रिया और सूत्रों के सहारे ही आगे बढ़ना होता है. यदि हमें आधिकारिक तरीके से कुछ मिल भी जाए तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बड़े टेढ़े सवाल पैदा हो जाएंगे."

इसके अलावा एक तीसरी भी दिक्कत है वह है यह साबित करना कि इन तीनों ने किस कानून का उल्लंघन किया था. इस हालत में जांच-पड़ताल चड्ढा से ही शुरू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसलिए करनी पड़ेगी ताकि यह साबित किया जा सके उन्होंने कर या विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन किया है.

यदि यह तय भी हो जाए कि बोफोर्स ने दलाली को करार समेटने का भुगतान कहकर सरकार को गुमराह किया, तो भी निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि सरकार उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी. पिछले पखवाड़े तक अधिकारी यही दोहरा रहे थे कि करार के मुताबिक दलालों को भुगतान की गई रकम की वापसी के लिए कंपनी से कुछ नहीं कहा जा सकता.

कंपनी को काली सूची में दर्ज करना भी संभव नहीं क्योंकि कंपनी अभी भी भारत को इन तोपों के लिए गोला-बारूद सप्लाई कर रही है. प्रतिबंध का मतलब होगा कि गोला-बारूद की सप्लाई बंद.

तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि बोफोर्स के साथ भविष्य में कभी कोई सौदा न किया जाए. लेकिन हकीकत यह है कि भारत में ही बोफोर्स तोप बनाने के करार पर जल्द ही सौदेबाजी शुरू होने वाली है. यह करार 1986 में 400 तोपों की सप्लाई के 1700 करोड़ रु. के करार के बराबर ही होगा.

आखिरी विकल्प है कि तोप सौदे को रद्द ही कर दिया जाए. लेकिन एक अधिकारी ने सफाई दी कि यह "हथियारों के लिए फ्रांसीसियों के हाथों खेलने" सरीखा होगा, क्योंकि विकल्प वही बचते हैं.

जाहिर है, सरकार बोफोर्स को उस हद तक रगड़ने के लिए तैयार नहीं जितना उसके लिए संभव भी है. और पूरी संभावना यही है कि बोफोर्स कोई भी जानकारी देने से इनकार करती रहे. बहरहाल, 'द हिंदू' के पहले रहस्योद्घाटन के बाद पिछले पखवाड़े चड्ढा ने बोफोर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष पेर ओव मोरबर्ग को टेलीफोन किया और उनसे 1978 में बोफोर्स के साथ हुए उनकी कंपनी एनाट्रॉनिक के करार की नकल भेजने को कहा. लेकिन उन्हें दो टूक जवाब दे दिया गया कि कंपनी किसी को किसी दस्तावेज की नकल नहीं देगी. यदि बोफोर्स भारत में अपने प्रशासनिक सलाहकार को ही घास नहीं डाल रही तो जाहिर है भारत सरकार के साथ भी सहयोग करने को तब तक तैयार नहीं होगी जब तक उसके साथ सख्ती नहीं बरती जाती.

बहरहाल, लगता है इस बार सरकार को अपनी साख कायम करने के लिए बोफोर्स और इसके पूर्व व वर्तमान दलालों और प्रतिनिधियों पर दबाव डालना ही पड़ेगा. इस बीच 'द हिंदू बम' तो फटने को तैयार है ही.

—टी.एन. नैनन

राघवेंद्र राव

एन. राम

"संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है"

यदि भारत में भी 'पुलित्जर प्राइज' जैसा कोई पुरस्कार दिया जाता तो निस्संदेह 'द हिंदू' के सह— संपादक एन. राम और उसकी जेनेवा संवाददाता चित्रा सुब्रमण्यम को दिया जाता. बोफोर्स घोटाले से संबंधित ताजा रहस्योद्घाटन के बाद एन. राम से बातचीत के अंश:

● ***आपके मुताबिक बोफोर्स से रिश्वत लेने वालों में भारतीय भी शामिल थे. क्या यह एक अनुमान भर नहीं है?***

मैं नहीं सोचता कि इसे कोई गलत भी साबित कर सकता है. हमारे पास इतने पुख्ता दस्तावेज हैं कि अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती. मैं यह भी कह सकता हूं कि हिंदू में छपे दस्तावेजों के अनुसार स्वेंस्का को 6 फीसदी कमीशन पिछले सौदे के लिए था. पता लगाना पड़ेगा कि यह सौदा किसलिए था.

● ***यानी आप यह नहीं मानते कि भुगतान 'करार समेटने' के लिए किए गए.***

दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि भुगतान दलाली के बतौर कुछ प्रतिशत के आधार पर किए गए. सौदा न होने पर कोई भुगतान नहीं होता. 'करार समेटने' वाली बात तो बाद में गढ़ी गई.

● ***लेकिन विन चड्ढा और मोइनिओ के साथ तो करार खत्म करने का समझौता हुआ था.***

मैं चड्ढा के बारे में तो नहीं जानता पर भुगतान प्राप्त करने वाली दो कंपनियों स्वेंस्का या ए.ई. सर्विसेज के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ. जहां तक तीसरी कंपनी मोइनिओ का ताल्लुक है, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि करार समेटने का समझौता कब हुआ था.

● ***क्या सरकार ने आपसे संपर्क किया?***

इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. वैसे, सरकार चाहे तो सभी जानकारियां स्वीडन के सरकारी वकील लार्स रिंगबर्ग और दूसरों के जरिये आसानी से पा सकती है. दरअसल रिंगबर्ग तो भारत सरकार की तरफ से कुछ पूछे जाने की प्रतीक्षा करते रहे.

● ***सरकारी एजेंसियों की मदद के बगैर अपनी पड़ताल आगे जारी रख सकेंगे?***

सरकार को इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि अब बहाना बनाने का कोई उपाय नहीं बचा है कि ये भुगतान दलाली के रूप में नहीं हुए. और यदि वह आगे नहीं कार्रवाई करती तो हम अपना काम जारी रखेंगे.

● ***क्या आप बता सकते हैं कि पैसा अंततः किसे पहुंचा?***

आगे की जांच करने के लिए काफी ठोस आधार बन गया है.

● ***विन चड्ढा का कहना है कि बोफोर्स के साथ 1981 में हुआ उनका समझौता भी 1978 के समझौते से मिलता-जुलता ही है और यह भी कि समझौते में वे प्रमुख शर्तें नहीं हैं जिन्हें आपने 1978 के समझौते के बतौर छापा है.***

उन्होंने हिंदू में प्रकाशित 1986 के समझौते को तो सही बताया है. 1978 के समझौते की प्रति भी हमें उसी स्रोत से मिली है. दिलचस्प बात यह है कि बोफोर्स कंपनी भी यही कहती है कि उसके पास पीटको व मोइनिओ के साथ 1979 में हुए समझौते की मूल प्रति नहीं है.

● ***क्या इस जांच को रोकने के लिए आप पर कोई दबाव डाला गया?***

कोई दबाव नहीं डाला गया.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

धमाकों से थमीं धड़कनें

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बम विस्फोटों का कहर

पिछले महीने पंजाब के आतंकवादियों ने अपने असीमित शस्त्रागार में से अब तक के सर्वाधिक घातक हथियार का इस्तेमाल किया जिससे कई जानें गईं. हाथ से बने ये विस्फोटक भीड़-भाड़ वाली चुनिंदा जगहों पर रखे गए थे.

पिछले हफ्ते तक भीड़-भरे बाजारों में इन बमों के फटने से 73 लोग मारे गए. इनमें दो बम अमृतसर शहर के बीचोबीच और एक-एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र और पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर में फटे. इसके अलावा 175 लोग घायल हुए जिनमें अधिकांश की हालत गंभीर है. कुरुक्षेत्र और दिल्ली में विस्फोट और अमृतसर में दूसरे धमाके की वारदातें 19 से 21 जून तक लगातार तीन दिन हुईं.

इन वारदातों के पीछे मकसद यह था कि विस्फोट ऐसी जगहों पर और ऐसे वक्त में किए जाएं जिससे हिंदू भड़ककर बदले की कोई कार्रवाई कर बैठें. स्वर्णमंदिर की मर्यादा बहाली के एक ही हफ्ते बाद पहले विस्फोट ने अमृतसर की अप्रत्याशित शांति भंग कर दी. इसमें 20 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हुए. ये सभी लोग जाने-माने शिवाला भाइयां मंदिर के बाहर इकट्ठे हुए हिंदू थे.

अमृतसर में दूसरा विस्फोट भी हिंदू बहुल इलाके कटरा अहलूवालिया में हुआ. कपड़े के इस बाजार में शाम छह से सात बजे तक खूब भीड़ रहती है. बम विस्फोट सात बजने के तुरंत बाद हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए और 50 घायल हुए.

संयोग से सांप्रदायिक गुस्सा हिंसा की लहर में नहीं बदला. विस्फोट के तुरंत बाद एक भारी भीड़ चौराहे पर जमा हो गई थी. लोगों में जबरदस्त गुस्सा था और वे पुलिस विरोधी नारे लगाते रहे. भीड़ ने फायरब्रिगेड कर्मचारियों को लाशें हटाने से भी रोक दिया. शुक्र है कि अगले दिन मृतकों की अंत्येष्टि के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया. यहां तक कि हरियाणा, जहां हिंदू प्रतिशोध की अत्यधिक संभावना रहती है, में भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़की. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. रविवार की सुबह कुरुक्षेत्र में भी उस समय बम विस्फोट हुआ जब टीवी की एक दुकान पर जमा भीड़ 'रामायण' धारावाहिक देख रही थी. इस वारदात में 20 लोग मारे गए. इसी तरह राज्य के पेहोवा कस्बे के एक सिनेमा हाल में आतंकवादियों ने छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. अगला निशाना भी बहुत सोच-समझकर चुना गया. अब पश्चिम दिल्ली के संवेदनशील इलाके तिलक नगर की सब्जी मंडी में बम विस्फोट हुआ.

इन सुनियोजित हमलों से केंद्र का यह दावा गलत सिद्ध हुआ कि मई में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद आतंकवादी संगठन बिखर गए हैं. इस ऑपरेशन की नाटकीय समाप्ति के बाद पंजाब के आला पुलिस अफसरों ने केंद्र से आग्रह किया था कि उन्हें अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जिलों के गांवों में आतंकवादियों से निबटने के लिए तुरंत सफाई अभियान चलाने की इजाजत दी जाए पर यह मांग रद्द कर दी गई. केंद्र ने गुप्तचर एजेंसियों की इन रिपोर्टों की भी अनदेखी कर दी कि आतंकवादी फिर से संगठित होकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में फैलने की कोशिश कर रहे हैं. हत्यारों पर दबाव बढ़ाने के बजाय केंद्र सरकार शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति के साथ राजनैतिक खेल खेलने लगी. उसका यह हथकंडा भी बुरी तरह नाकाम रहा.

इस बीच उग्रवादियों को अपने नुकसान का लेखा-जोखा करने, फिर से संगठित होने और दुबारा हमले शुरू करने के लिए काफी वक्त मिल गया. प्रारंभिक जांच के मुताबिक इन विस्फोटों के पीछे बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) का हाथ है. ये दोनों गुट ऑपरेशन ब्लैक थंडर से मुख्यतः अछूते रहे हैं. सुरक्षा बलों के आगे आत्मसमर्पण करने वाले तीनों 'बब्बर' दरअसल छोटे दर्जे के कार्यकर्ता थे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनसे की गई पूछताछ से कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इसी तरह केसीएफ के दर्जन भर में से दो गिरोहों के ही कुछ लोग स्वर्णमंदिर की कार्रवाई में मारे गए थे. इन

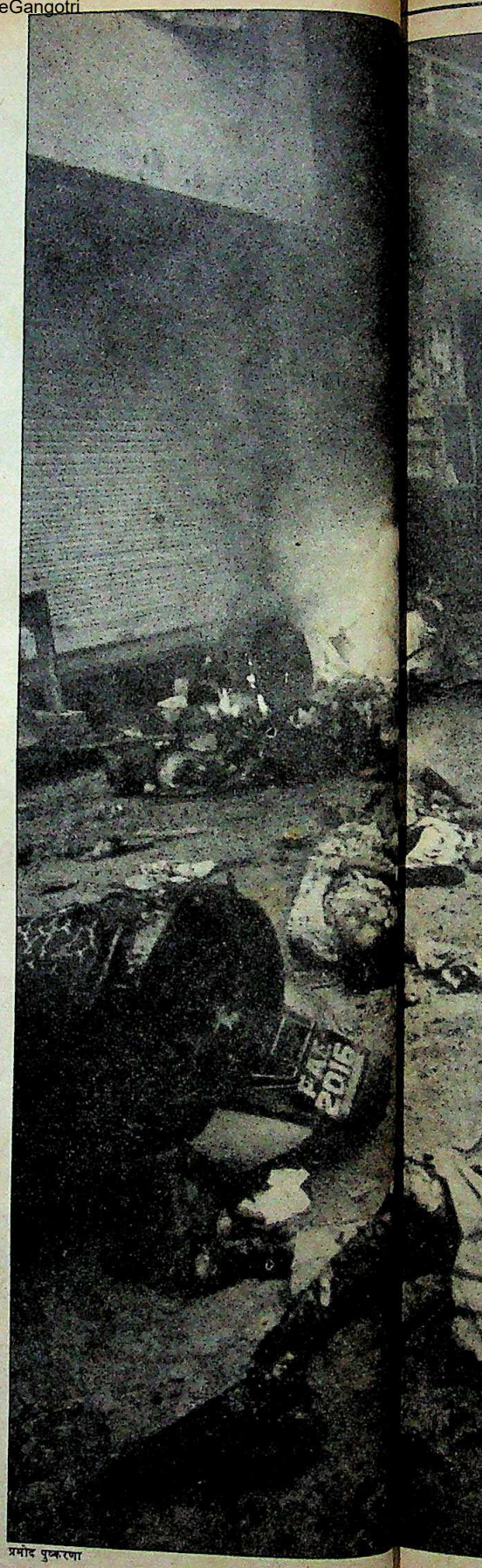

अमृतसर के कटरा अहलूवालिया में बम विस्फोट के चंद मिनटों बाद का हौलनाक दृश्य

प्रमोद पुष्करणा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

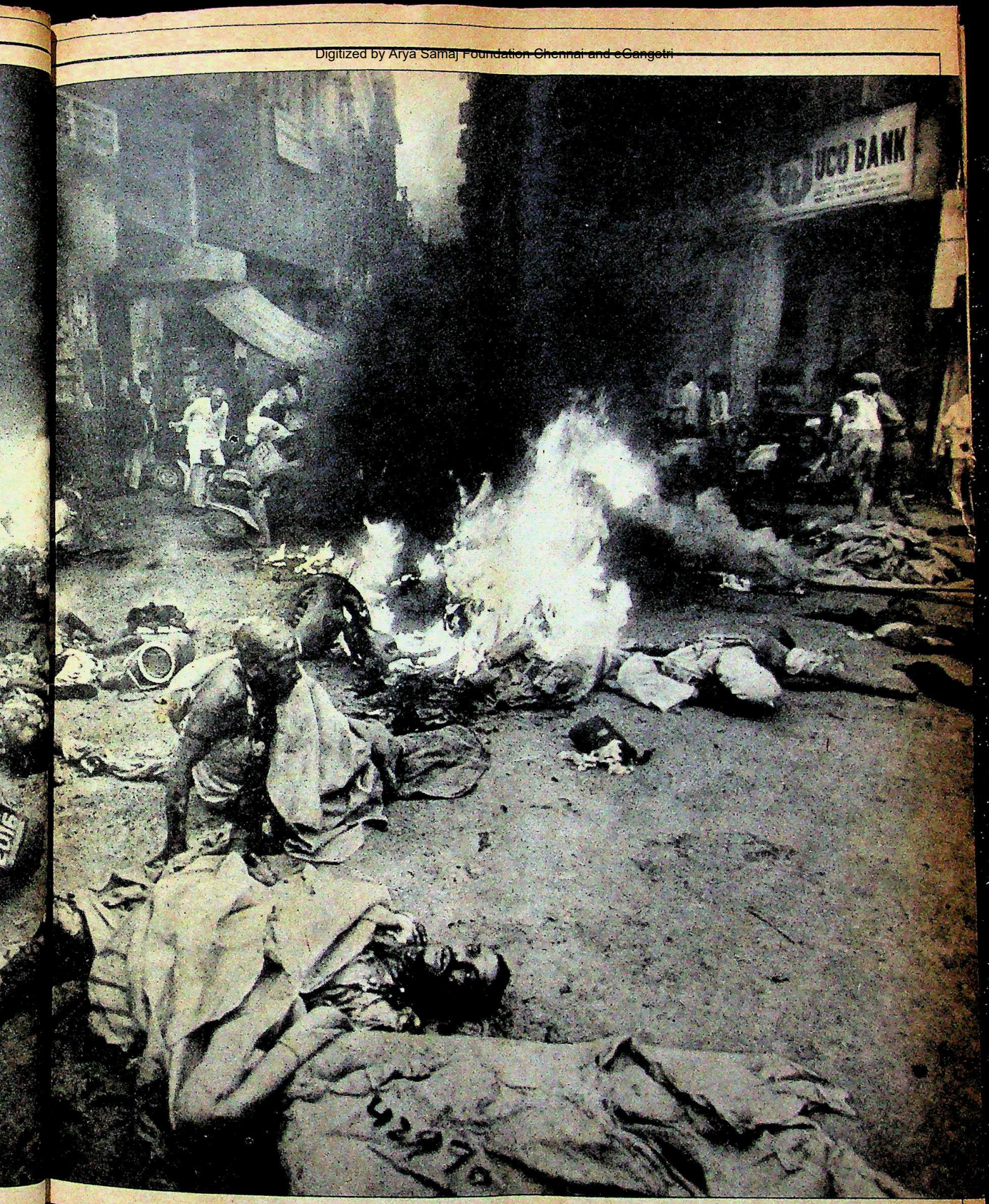

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोनों आतंकवादी संगठनों ने जो थोड़ा-बहुत नुकसान उठाया उसकी भरपाई हाल ही की इन रिपोर्टों से होती है कि बब्बर खालसा ने केसीएफ से गठजोड़ कर लिया है.

और दोनों की संयुक्त कार्रवाई बेहद घातक है. हालांकि वे अब निहायत देसी और आसानी से बनाए जा सकने वाले बम इस्तेमाल कर रहे हैं पर वे काफी तबाही करने में सक्षम हैं. दो से तीन किलोग्राम के इन विस्फोटकों में जिलेटिन की छड़ों के साथ पोटेशियम फॉस्फेट, पिकरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिला होता है. इनके अलावा इनमें फ्यूज प्लग और समय निर्धारित करने के लिए एक अस्थायी छड़ जैसा यंत्र भी लगा रहता है. टाट के बोरों और वनस्पति घी के कनस्तरों में छिपे इन बमों को खोज पाना वस्तुतः असंभव है.

कुरुक्षेत्र और दिल्ली में हुए विस्फोटों के बाद केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. इसमें गृहमंत्री बूटा सिंह और वरिष्ठ अधिकारी एक बात पर सहमत हुए कि आतंकवादियों की ताजा चाल से निबटना आसान नहीं होगा. उनका मानना था कि जनता को भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने के खतरों और किसी संदिग्ध दिखने वाली वस्तुओं की जानकारी पुलिस को तुरंत देने के महत्व के प्रति जागरूक बनाना ही एकमात्र कारगर रणनीति हो सकती है. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं, "हाल के हमले अप्रत्याशित नहीं थे. ऐसी अनेक खुफिया चेतावनियां मिली थीं कि आतंकवादी कई जगह एक साथ वार कर सकते हैं." इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्य होता है कि केंद्र ने पहले से सुरक्षात्मक प्रबंध करने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई.

बहरहाल, इन हत्याओं से जहां केंद्र सरकार हिल उठी, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल भी हतप्रभ रह गए. उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने सीआरपी की 12 कंपनियां और विभिन्न किस्म के 1700 हथियार भेजने की उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है. यह मांग उन्होंने पिछले महीने पानीपत में हुई 14 लोगों की हत्या के बाद की थी. अभी तक हरियाणा को सीआरपी की तीन कंपनियां, 300 सेल्फ लोडिंग राइफलें, 250 स्टेनगनें और 20 मशीनगनें ही मिली हैं. वैसे देवीलाल की यह मांग कुछ हद तक वाजिब भी है क्योंकि पिछले महीने हरियाणा में पांच बार ऐसी घटनाएं हुई हैं. दरअसल पंजाब की खुफिया एजेंसियों ने कुरुक्षेत्र जिले की पुलिस को संभावित हमलों के प्रति आगाह भी किया था. आखिरी खुफिया सूचना तो सीआरपी के अमृतसर मुख्यालय ने कुरुक्षेत्र के बम विस्फोट से तीन ही दिन पहले भेजी थी. लोकदल के

प्रशांत पंजियार

विस्फोट में घायल व्यक्ति की व्यथा सुनते देवीलाल

वयोवृद्ध नेता कहते हैं, "हमने केंद्र को कहा है कि वह हरियाणा से भी पंजाब के बराबर सलूक करे. समस्या यहां भी गंभीर होती जा रही है." लेकिन अतिरिक्त बलों और हथियारों की हरियाणा की मांग को केंद्र ने अनसुना कर दिया, हालांकि हाल की वारदातों के बाद देवीलाल की अगुआई वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने बूटा सिंह से मुलाकात के दौरान यह मुद्दा फिर उठाया था.

लेकिन देवीलाल का गुस्सा अकेले केंद्र सरकार पर ही नहीं उतरा. उन्होंने पेहोवा के एक इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को मुअत्तिल कर दिया. जिस सिनेमा हॉल में विस्फोट हुआ वह उस इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में ही पड़ता था और उसके मातहत दोनों सिपाही गश्त के दौरान वहां नहीं पहुंचे थे. देवीलाल ने पुलिस महानिदेशक हंसराज स्वान का भी तबादला करके उनकी जगह एस.एस. ब्राड को नियुक्त किया. इसके साथ ही सीआईडी के उपमहानिरीक्षक ए.एस. भाटोटिया का भी तबादला कर दिया गया.

लेकिन पुलिसवालों के खिलाफ देवीलाल की दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद हत्याओं के ताजा दौर से एक बात साफ हो गई है कि पुलिस आतंकवादियों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी. यहां तक कि देश का सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रबंधों वाला शहर दिल्ली भी आतंकवादियों की शिकारगाह सिद्ध हुआ. दरअसल तिलक नगर में बम विस्फोट के समय राजधानी में सबसे कड़े सुरक्षा प्रबंध थे क्योंकि एक ही दिन पहले कुरुक्षेत्र में बम फटने की घटना हो चुकी थी. लेकिन घर-घर तलाशी के बावजूद जिस कार से बम फेंका गया था, पुलिस न तो उसे पकड़ पाई और न आतंकवादियों को. दिल्ली के पुलिस आयुक्त विजयकरण मानते हैं, "इन हमलों को रोकने का कोई सटीक तरीका नहीं है."

इस बीच केंद्र ने हमेशा की तरह तथ्यों और आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने की अपनी महारत का फिर प्रदर्शन किया. इन बम विस्फोटों को वह अपने इस दावे को पुष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है कि पाकिस्तान से आतंकवादियों को मिलने वाले आधुनिक हथियारों की तस्करी पर बहुत हद तक अंकुश लग गया है. इसके पीछे तर्क यह है कि हथियारों के न मिलने की वजह से आतंकवादी अब देसी बमों का प्रयोग करने पर मजबूर हुए हैं. सरकार का दावा है कि मई में हथियारों के साथ सीमा पार करते 57 लोग मारे गए और जून में यह आंकड़ा और बढ़ जाने की उम्मीद है.

लेकिन आतंकवादियों और निर्दोषों की हत्याओं, हथियारों और गोला-बारूद की जब्ती, पाकिस्तान में चलने वाले कथित आतंकवादी शिविरों और एक राज्य से दूसरे में आने-जाने वाली सीआरपी की कंपनियों के आंकड़ों के अंबार में एक महत्वपूर्ण सवाल छिपता जा रहा है और वह है पंजाब समस्या का राजनैतिक समाधान. जब तक यह समाधान नहीं निकलता कोई भी रणनीति, चाहे वह कितनी ही कारगर क्यों न हो, आए दिन मौत के तीव्र होते तांडव को नहीं रोक पाएगी.

—विपुल मुद्गल अमृतसर में और पंकज पचौरी कुरुक्षेत्र में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

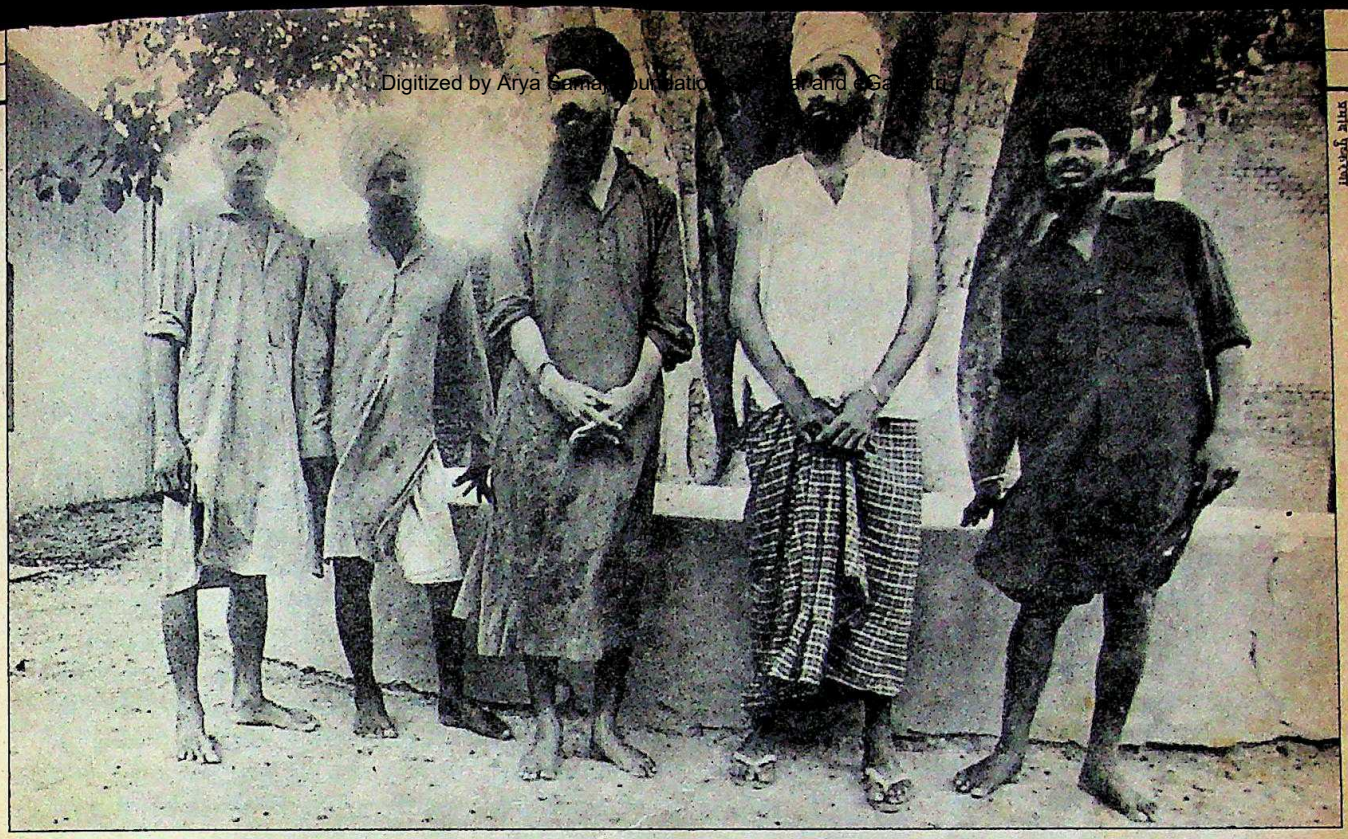

गिरफ्तार आतंकवादी

संगीन सूचनाओं के स्रोत

सुनियोजित अलगाववादी आंदोलन के सूत्रों के सुराग मिले

पंजाब में आतंकवाद से जूझ रहे वरिष्ठ अधिकारी सूचनाओं का 'गुप्त खजाना' हाथ लग जाने से फूले नहीं समा रहे. इन अधिकारियों का दावा है कि ये सूचनाएं उन्हें ऑपरेशन ब्लैक थंडर में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान मिलीं. वाकई कुछ रहस्योद्घाटन तो बेहद सनसनीखेज हैं. मसलन शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की हत्या की साजिश. और यह भी कि आतंकवादियों की प्रमुख योजनाएं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों द्वारा बनाई जाती हैं जिनके बारे में खुद आतंकवादियों को कोई इल्म नहीं है. बहरहाल, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले पखवाड़े 'इंडिया टुडे' को दिखाई गई रिपोर्टें केंद्र के माफिक हैं.

लेकिन पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूंछताछ से मिली जानकारी एकदम पक्की है और इसकी प्रमाणिकता के लिए उन्होंने पूछताछ की पूरी कार्रवाई की वीडियो टेप बना रखी है. अगर यह सच है तो आतंकवादियों के इकबालिया बयान निश्चत तौर पर महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले हैं.

रेखाचित्र: प्रियली दत्त गुप्त

पुलिस अधिकारी यह जानकर हैरान रह गए कि कुख्यात निरवैर सिंह सारे खेल का अगुआ नहीं था. वह पंथक समिति के सदस्यों को भी भली-भांति नहीं जानता था

ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान पकड़े गए प्रमुख आतंकवादी पूछताछ केंद्र में

बेहद सनसनीखेज पहलू तो यह है कि पंजाब में आतंकवादियों की हालत वैसी नहीं है जैसी कि पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय और उनके सलाहकार जूलियो रिबेरो दावा करते रहे हैं. उनका दावा रहा है कि कुछ प्रमुख आतंकवादी नेताओं के सफाए से इस आंदोलन की रीढ़ टूट जाएगी. ब्लैक थंडर के दौरान पकड़े गए 50 प्रमुख आतंकवादियों की पूछताछ से यही साबित होता है.

इस पूछताछ के आधार पर तैयार की गई रिपोर्टों के मुताबिक पंजाब के कुछ दुर्दांत आतंकवादी तो बाहर से चलाए जा रहे सुनियोजित अलगाववादी आंदोलन के कठपुतले भर हैं. यह काम दो स्तरों पर होता लगता है. पाकिस्तान में गुप्त अड्डों और दूसरे देशों में रह रहे अज्ञात आतंकवादी नेता रणनीति गढ़ने के साथ-साथ मौत के वारंट जारी करते हैं जबकि देश के सबसे खूंखार आतंकवादी उनकी इच्छाओं की तामील भर करके महज हत्यारों की भूमिका निभाते हैं. 'ए' श्रेणी के अधिकांश आतंकवादियों को भी अपने असली आकाओं या उनकी अगली योजनाओं का अता-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पता नहीं होता.

आतंकवादी चंचल सिंह उधोके ने पूछताछ करने वालों को बताया कि सभी हत्याओं का फैसला पाकिस्तान में बैठे कुछ अज्ञात लोग करते हैं. सिर्फ जनसंहारों में ही आतंकवादियों को बिना सोचे-समझे हत्या करने की छूट होती है.

पंजाब में उधोके को 'लेफ्टिनेंट जनरल' सुखदेव सिंह झमके से निर्देश मिलते थे जो खुद पाकिस्तानी अड्डों में बैठे दूसरे नेताओं से आदेश पाता था. उधोके ने माना, "एक दिन झमके ने मेरे पास आकर बताया कि उसे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की हत्या का निर्देश मिला है. एक कागज पर ठाकरे का नाम लिखा था और नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति के दस्तखत थे. झमके ने मुझे पेंटा के भाई परमजीत सिंह काला के साथ बंबई जाने को कहा. हमें एक स्टेनगन और एक रिवाल्वर सहित उस व्यक्ति का पता थमा दिया गया जिससे हमें बंबई में मिलना था. बंबई पहुंचने पर हमारे संपर्क सूत्र ने हमें एक सफेद फिएट कार में इधर-उधर घुमाया. सात-आठ दिन तक हम ठाकरे का पीछा करते रहे पर उसकी हत्या करने का मौका हाथ नहीं लगा. तब हमने वापस लौटने का फैसला किया."

लेकिन पुलिस अधिकारी इस जानकारी से हैरान रह गए कि आत्मसमर्पण करने वालों में प्रमुख शख्स निरवैर सिंह इस सारे खेल का अगुआ नहीं था. निरवैर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पंथक समिति के सदस्यों को भली-भांति जानता भी नहीं. उसे हरकारों से लिखित संदेश और मौत के वारंट मिलते थे. उसे यह भी नहीं पता था कि हरकारों को किससे और कहां से आदेश मिला करते थे.

मलकियत सिंह को कागज की एक पुर्जी पर लिखे आदेश स्वर्णमंदिर में गुप्त वेश में आने वाले हरकारों से मिला करते थे. पिछले साल एक पुर्जी पर अकाली नेता ओंकार सिंह मत्तेनंगल के नाम के नीचे वैसे ही दस्तखत करके भेजे गए थे. उसने बताया, "शाम को मैं दो साथियों के साथ बिना हथियार लिए बाहर आया. बस में बैठकर हम गुरु का बाग पहुंचे. वहीं एक डेरे में मनबीर सिंह चहेड़ू ('ए' श्रेणी का आतंकवादी) के एक संपर्क ने हमें एके-47 राइफिलें और गोला-बारूद दिया. फिर हम मत्तेनंगल के गांव गए. वे नहीं मिले तो उनके बेटे को ही गोली मार कर हम लौट आए."

मलकियत सिंह ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसे कागज की पुर्जियों पर लिखे हुए आदेश स्वर्णमंदिर में छद्म वेश में आने वाले हरकारों से मिला करते थे

मनोछल का संपर्कसूत्र जगतार सिंह लंगा हथियाई रकम या कोई संदेश देने के लिए अक्सर पंथक समिति के डिक्टेटर से मिला करता था. जगतार सिंह ने बताया, "पिछले एक साल में मनोछल दो बार ही स्वर्णमंदिर में आया होगा. अमूमन मैं उससे मिलने जाया करता और मंदिर में इकट्ठी की गई रकम उसे सौंप आता. मुझे हरकारों की मार्फत संदेश मिलते थे जिन्हें मैं जागीर सिंह या निरवैर सिंह तक पहुंचा दिया करता."

पूछताछ में कई और हैरतअंगेज तथ्य भी सामने आए हैं. प्रायः सभी आतंकवादियों को यकीन है कि पाकिस्तान की मदद से जल्दी ही खालिस्तान बन जाएगा और वे सभी 'ऊंचे ओहदों' पर बैठेंगे. एक महत्वपूर्ण बात यह भी पता चली कि आत्मसमर्पण कर चुके अधिकांश आतंकवादी या तो निरक्षर हैं या फिर प्राइमरी जमात से स्कूल छोड़ चुके हैं. इसके अलावा वे गरीब परिवारों से हैं जिनके पास दो से पांच एकड़ तक ही जमीन है.

पर अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि इन इकबालिया बयानों से आतंकवादियों की भर्ती करने की प्रक्रिया झलकती है. इसमें निरवैर सिंह एक प्रमुख माध्यम था. सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ करने वालों को बताया कि दर्जनों लोग स्वर्णमंदिर के कमरा नं. 14 में उससे मिलने आया करते थे. और वे अपने-अपने गांव को फरार आतंकवादियों की पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश करते थे. पर उसके सभी रंगरूट ज्यादातर किशोर ही थे जो मारे गए आतंकवादियों के बेटे या रिश्तेदार थे. दूसरा मजेदार पहलू यह है कि पंजाब में सक्रिय आतंकवादी गुटों का आपस में कोई तालमेल नहीं है.

गोरखा उग्रवादियों से मनोछल के संबंधों के बारे में भी आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं. पूछताछ की रिपोर्टों के मुताबिक पंथक समिति का यह मुखिया 'गोरखालैंड' के उग्रवादियों से मिलने कुछ महीने पहले आसनसोल गया था. पर यह मालूम नहीं कि उनके बीच क्या बातें हुईं. उसने मद्रास में तमिल मुक्ति चीतों और आंध्र प्रदेश के नक्सलवादियों को भी अपने संदेश भेजे थे.

मनोछल के संपर्कसूत्र जगतार सिंह लंगा ने बताया कि वह मंदिर में जबरदस्ती वसूल की गई रकम या कोई संदेश देने के लिए अक्सर पंथक समिति के डिक्टेटर से मिलता था

पूछताछ की ये रिपोर्टें अगर सही हैं तो इनसे पंजाब में आतंकवादियों के फैले जाल के बारे में कई मिथक भरभर कर ढह जाते हैं. बहरहाल, इनसे यही जाहिर होता है कि उनका खतरा अभी बरकरार है, भले ही उनका संचालन कहीं दूर बैठकर क्यों न किया जा रहा हो.

—विपुल मुद्गल चंडीगढ़ में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

एक और पराजय

पार्टी में असंतोष का खामियाजा

इलाहाबाद और अन्य उपचुनावों के नतीजों को राजीव की 'नैतिक हार' बताकर रामकृष्ण हेगड़े जैसे मुश्किल में फंस गए. 19 जून को स्नातकों और अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद की छह सीटों के द्विवार्षिकी चुनावों में जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. हेगड़े इस हार को स्वीकार करते हुए बोले, "हां, एक तरह से यह मेरी भी नैतिक हार है, लेकिन मैं इस बात से तसल्ली कर सकता हूं कि उपचुनावों की तरह यह प्रत्यक्ष आम चुनाव नहीं था."

कर्नाटक हाई स्कूल सहायक अध्यापक संघ के उम्मीदवारों ने जहां अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की तीन सीटें जीतीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की तीनों सीटें भाजपा के हाथ आईं. जनता पार्टी को दुख इस बात का है कि यदि बागी नेता एच.डी. देवगौडा और हेगड़े आपसी मतभेद भुला देते तो इन छह में से चार सीटें उसे जरूर मिल जातीं. प्रदेश जपा अध्यक्ष एम.पी. प्रकाश कहते हैं, "यह हार पार्टी की अंदरूनी फूट के कारण ही हुई." चुनाव में हारे जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रो. बी.के. चंद्रशेखर कहते हैं, "पार्टी की अंदरूनी कलह का खामियाजा मुझे भरना पड़ा." लेकिन देवगौडा जैसे पल्ला झटकते हुए बोले, "इसमें मेरा क्या दोष है? यहां पार्टी के भीतर असंतोष तो पिछले दो वर्षों से है."

इस हार की शर्म छिपाने के कई बहाने जपा नेताओं ने ढूंढ़ निकाले हैं. राजस्वमंत्री एस.आर. बोम्मई कहते हैं, "कुछ अंदरूनी समस्याओं के कारण उम्मीदवारों का चयन ही देर से हुआ. इस कारण चुनाव प्रचार के लिए हमें वक्त नहीं मिल पाया." उधर हेगड़े का कहना है कि "जरूरत से ज्यादा आत्मसंतोष और संगठन की कमजोरी पार्टी को बहुत महंगी पड़ी है." लेकिन इन परिणामों से यह बात साफ हो गई है कि शहरी शिक्षित मतदाता जो कभी पार्टी के मुख्याधार हुआ करते थे, अब इससे दूर होते जा रहे हैं. जपा के लिए तसल्ली की बात यही रही कि इन चुनावों में इंका तीसरे नंबर पर और बेहद कमजोर स्थिति में रही.

लेकिन चुनावी मोर्चे पर हार की कुछ हद तक खानापूरी राज्य सरकार ने विधान-सभा में विनियोग विधेयक पास करवा के कर ली है. इस विधेयक में इस वर्ष 4,843 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी. देवगौडा का गुट इस विधेयक के विरोध में वोट देता तो हेगड़े सरकार गिर सकती थी. देवगौडा ने घोषणा कर दी थी कि उनका गुट इस विधेयक के पक्ष में वोट डालेगा, बशर्ते हेगड़े किसानों को सिंचाई के लिए धनराशि देने की व्यवस्था करें. इन दबावों के कारण हेगड़े ने इसके लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय खोजने के लिए एक सर्वदलीय विधायिका समिति का गठन किया था. हेगड़े के इस कदम ने बागी गुट को इस विधेयक के पक्ष में वोट डालने को विवश कर दिया.

इस दौरान देवगौडा सार्वजनिक सभाओं में खुद को किसानों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं.

भवान सिंह

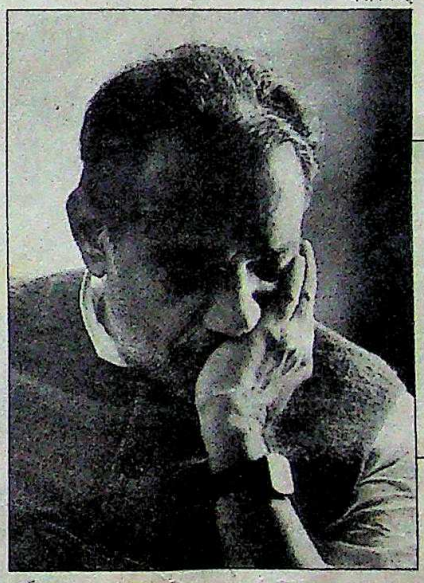

उल्लेखनीय बात यह है कि आर. गुंडुराव की इंका सरकार 1981-82 में हुए हिंसक किसान आंदोलन के कारण ही गिरी थी. लेकिन हेगड़े को पूरा यकीन है कि इस बार इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा, "किसानों को मेरे खिलाफ भड़काना इतना आसान नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरी सरकार ने अपनी सामर्थ्य भर हर तरह से उनकी मदद की है." मुख्यमंत्री का कहना है कि गौडा किसानों की आड़ में अपनी असली मंशा—जातिवादी भावनाओं को उभारना—पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं.

गौडा ने अब प्रकाश की जगह अपने समर्थक और पूर्व मंत्री सिद्धरमैया को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की जिद छोड़ दी है. गौडा बताते हैं, "अब चूंकि परिषद के चुनाव लगभग हो चुके हैं, इस मांग का कोई औचित्य नहीं रह जाता." इससे साफ हो जाता है कि देवगौडा पार्टी अध्यक्ष के पद पर अपने समर्थक को इसलिए बैठाना चाहते थे कि अपनी पसंद के उम्मीदवारों को खड़ा करा सकें. लेकिन हेगड़े के इनकार करने पर देवगौडा ने चुनाव के पहले दौर में दो बागी उम्मीद-वारों को जितवा कर इसका बदला लिया, और ध्यान रखा कि चुनाव के दूसरे दौर में पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार न जीत पाए.

देवगौडा ने चेतावनी दी है कि "यदि महीनेभर में हेगड़े सरकार ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो उसे भयंकर नतीजे भुगतने पड़ेंगे." अब उनकी दो मांगें हैं— हेगड़े सिंचाई के लिए पर्याप्त कोष रखें, और भ्रष्ट और निकम्मे प्रशासन को दुरुस्त बनाएं." हेगड़े भी मानते हैं कि "सिंचाई पर और रकम-खर्च की जानी चाहिए. लेकिन समस्या यह है कि रकम जुटाएं कैसे? जहां तक प्रशासन को चुस्त बनाने का सवाल है, मैं मानता हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है. लेकिन यहां समस्या यह है कि विधायक

परिषद चुनावों में हार के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेगड़े असंतोष को दबाएंगे या इस्तीफा दे देंगे या विधानसभा को भंग करा देंगे

वर्षों से ढीले प्रशासन के आदी हो चले हैं. मैं भी इस ओर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूं."

परिषद चुनाव के तीसरे और अंतिम दौर के लिए 3 जुलाई को 58,000 जिला परिषदों और मंडल पंचायतों के सदस्य 22 उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे. इंका और जपा के एक-एक उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं. जपा इस चुनाव में 17 सीटें जीत सकती है, पर हेगड़े बागियों के हाथ पहले ही तीन सीटें गंवा चुके हैं. और जपा के मतभेदों के चलते इंका सात से ज्यादा सीटें जीत सकती हैं.

पिछले पखवाड़े हेगड़े के आगामी कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे असंतोष पर काबू पाएंगे या इस्तीफा देंगे या विधानसभा भंग करेंगे. वे क्या निर्णय लेते हैं, इसका पता तो अब 3 जुलाई के बाद ही चल पाएगा.

—अनीता प्रताप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

जमीन का जंजाल

हेगड़े की मुश्किलों का अंत नहीं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े असंतुष्टों के हाथों मिले अपमान के घूंट अभी हलक तले उतार भी नहीं पाए थे कि हाल ही में खत्म हुए विधानसभा सत्र में वे एक और हमले की जद में आ गए. आरोप है कि उनके रिश्तेदारों को सारे नियम-कानून ताक पर रखकर बंगलूर की बेहद कीमती जमीन मुहैया कराई गई. पहले-पहल मार्च में विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने वाले इंका विधायक के.एन. नागेगौडा कहते हैं, "यह शहर के सबसे बड़े जमीन घोटालों में एक है."

बावेला जयनगर रिहायशी इलाके की 22,662 वर्गमीटर जमीन पर है जिसे रेवाजीतू बिल्डर्स ऐंड डेवेलपर्स ने पिछले सितंबर में खरीदा था. इस कंपनी के 19 भागीदारों में एक शोभा मखीजा भी हैं जो हेगड़े के दामाद मनु निचानी की बहन हैं.

मगर इंका द्वारा लगाए गए ज्यादातर आरोप अदालत में नहीं टिक पाएंगे क्योंकि विधानसभा में विपक्ष के नेता के. नागरत्नम्मा यह दावा करके भारी भूल कर बैठे कि 'रेवाजीतू' हेगड़े की नातिन के नाम पर है. बहरहाल, लगता यह है कि रेवाजीतू बिल्डर्स ने कानून के उल्लंघन से ज्यादा उसकी खामियों का ही इस्तेमाल किया है.

आश्चर्यजनक बात तो इस सौदे को पूरा करने में दिखाई गई फुर्ती है. आवास एवं शहरी विकास विभाग के तीन अधिकारियों ने एक ही दिन में रेवाजीतू की फाइल को हरी झंडी दे दी. और आवेदन के एक महीने के अंदर ही सरकार ने जमीन बेचने की मंजूरी दे दी. लेकिन तत्कालीन आवास एवं शहरी विकासमंत्री और अब कानूनमंत्री ए. लक्ष्मीसागर कहते हैं, "सौदे की मंजूरी में मेरी अनावश्यक रुचि का आरोप राजनीति से प्रेरित है." हेगड़े कहते हैं, "इस मामले से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है."

मगर जमीन की कीमत कम आंकने के ठोस सबूत हैं. रेवाजीतू बिल्डर्स ने नारायणस्वामी ऐंड संस से 90 लाख रु. में इसका सौदा किया जबकि बाजार भाव से इसकी कीमत कम-से-कम 2.2 करोड़ रु. होती. राजस्वमंत्री एस.आर. बोम्मई भी मानते हैं कि फर्म ने इस सौदे में करीब 10 लाख रु. की स्टांप ड्यूटी नहीं भरी है पर वे कहते हैं, "कीमत कम आंकने की जानकारी मिलते ही हमने जांच का आदेश दे दिया और इस सौदे से संबंधित सब-रजिस्ट्रार को मुअत्तिल भी कर दिया."

इस पर भी बवाल मचा है कि आम तौर पर मीनमेख निकालने वाले अफसरों ने जमीन की बिक्री में आड़े आने वाली शहरी जमीन हदबंदी कानून की पेचीदगियों पर काबू पाने में नारायणस्वामी ऐंड संस की मदद की. 24,286 वर्गमीटर में से 19,638 वर्गमीटर जमीन हदबंदी कानून से अधिक थी. लेकिन 17 जुलाई 1985 को सरकार ने जमीन के मालिकों की इस दलील पर कि जल्दी ही वहां एक ग्रेनाइट कारखाना लगाया जाएगा, 16,194 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी. लेकिन आवास एवं शहरी विकास विभाग ने बाकी 3,444 वर्गमीटर जमीन के अधिग्रहण के लिए कोई कदम नहीं उठाया.

बाद में जनवरी 1987 में नारायणस्वामी ऐंड संस ने अपनी अधिक जमीन को हदबंदी कानून की धारा 20 (1) (8) के तहत बेचने की इजाजत मांगी. इसके तहत 'अत्यधिक कठिनाई' की हालत में जमीन बेचने की अनुमति है. हालांकि वे रेवाजीतू बिल्डर्स को 22,662 वर्गमीटर जमीन बेचना चाहते थे पर उन्हें 19,638 वर्गमीटर की ही मंजूरी लेनी थी. बाकी तो वे हदबंदी कानून के तहत बची अपनी जमीन से ही बेच सकते थे. लेकिन शहरी विकास विभाग के सचिव ने 19,164 वर्गमीटर बेचने की ही अनुमति दी.

तब नारायणस्वामी ऐंड संस ने पिछले मार्च में एक ताजा प्रस्ताव रखा कि 4.76 लाख रु. के 14 कर्जों के भुगतान के लिए उन्हें बाकी 3,444 वर्गमीटर जमीन भी बेचनी पड़ेगी. लेकिन शहरी विकास विभाग के संबंधित संयुक्त सचिव ने पाया कि 13 कर्जे वैध नहीं हैं क्योंकि वे वचनपत्रों के तहत लिए गए हैं. इसके अलावा अगर मंजूरी दे दी जाए तो इससे 'गलत मिसाल' ही कायम होगी. इसके बजाय अधिकारी का सुझाव था कि हदबंदी कानून की धारा 20 (1) (ए) के तहत 'सार्वजनिक हित' में बिक्री की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि रेवाजीतू बिल्डर्स इस जमीन को सामूहिक आवास योजना के लिए इस्तेमाल करेगी.

बहरहाल, 28 अप्रैल 1987 को सरकार ने बाकी 3,444 वर्गमीटर को भी बेचने की मंजूरी दे दी.

आखिर यह सौदा जल्दबाजी में 30 सितंबर 1987 को पूरा हुआ, शायद इसलिए कि 1 अक्तूबर से केंद्र का वह आदेश बंगलूर और अहमदाबाद में लागू

विवादास्पद जमीन

मुश्ताक अहमद

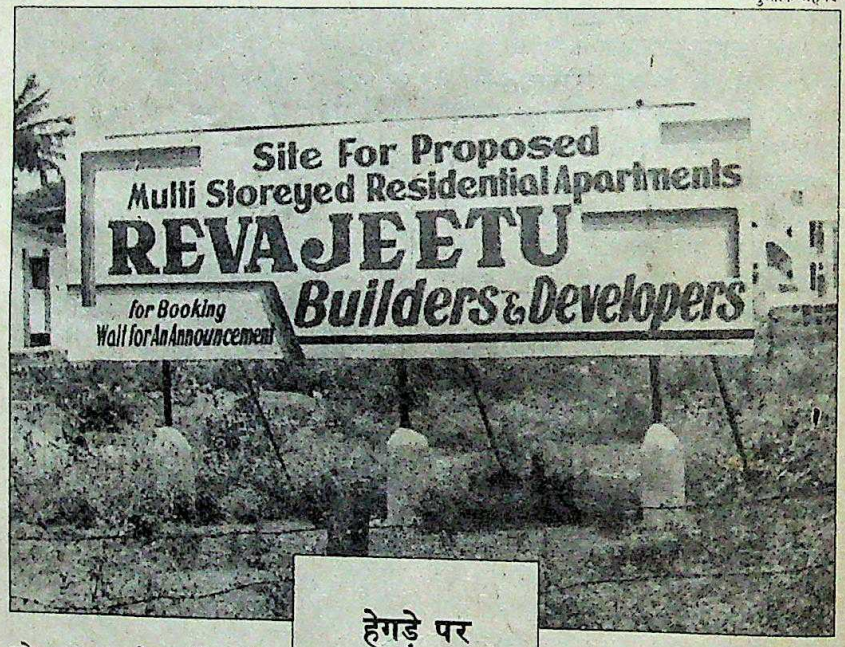

हेगड़े पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बंगलूर की बेहद कीमती जमीन मुहैया कराई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हो जाता कि 10 लाख रु. से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर आयकर विभाग की मंजूरी लेना जरूरी है.

लेकिन इस तर्क को न मानते हुए शहर के एक वकील एस. वासुदेव ने पिछले महीने एक याचिका में हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि सौदा रद्द करके जमीन जब्त कर ली जाए और आयकर विभाग बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करे. उधर 16 जून को इस मुद्दे पर विधानसभा में अध्यक्ष बी.बी. बंकर द्वारा सिर्फ सीमित बहस की मंजूरी देने और सरकार द्वारा सीबीआई जांच की मांग न मानने से क्षुब्ध इंका विधायक सदन का बहिष्कार कर गए. जनता पार्टी के असंतुष्ट नेता एच.डी. देवगौडा ने कहा, "कम-से-कम विधानसभा में गलती मान लेने की मुझ में ईमानदारी तो है. मैं उन लोगों की तरह नहीं जो अपने रिश्तेदारों के क्रियाकलापों पर बहस को रोकने के लिए सदन की नियमावली की आड़ लेते हैं."

अपने परिवार को विभिन्न घोटालों में घसीटने की इंकाई कोशिशों से झल्लाकर हेगड़े कहते हैं, "मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए एक अभियान चल रहा है. उन्हें उम्मीद है कि इससे तंग आकर मैं इस्तीफा दे दूंगा." —अनीता प्रताप

केरल

अपने भी नाराज

मार्क्सवादियों से असंतोष

केरल में 15 माह के शासन में मार्क्सवादियों ने अपने दोस्तों और हमदर्दों की हमदर्दी खोने के सिवा शायद और कुछ नहीं किया है. एक ओर तो सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (वालोमो) में उनके साझीदार अपने को दरकिनार किए जाने से नाराज हैं, दूसरी ओर चिड़चिड़ी नौकरशाही को शिकायत है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है.

और जैसे-जैसे नाराजगी बढ़ती जा रही है, मार्क्सवादियों के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ई.के. नयनार ने पिछले महीने पालघाट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कड़े शब्दों में कहा, "नौकरशाही का प्रभुत्व हम सहन नहीं करेंगे." और उधर माकपा की राज्य शाखा के महासचिव वी.एस. अच्युतानंदन ने कहा, "यह तो बदलाव लाने वाली सरकार है. सचिवों को यह समझ लेना चाहिए."

दरअसल यह चेतावनी मई के अंतिम हफ्ते में विभिन्न विभागों के सचिवों की मुख्य सचिव नारायण स्वामी के साथ हुई मासिक बैठक में हुई चर्चा के संदर्भ में थी. नौकरशाह चाहते थे कि माकपा की जोर-जबरदस्ती के बारे में मुख्य सचिव स्वामी मुख्यमंत्री नयनार तक उनकी शिकायत पहुंचाएं. उन्होंने शिकायत की कि उनमें से कइयों के खिलाफ खुफिया जांच शुरू कर दी गई है और उनके दफ्तरों के क्लर्क और चपरासी उनके कामकाज के बारे में माकपा तक खबर पहुंचा रहे हैं.

मार्क्सवादियों को नौकरशाहों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारी कांग्रेस (इ) से सहानुभूति रखते हैं. इसी संदेह के कारण कई जिलाधीशों के अलावा दूसरे कई पद भी खाली पड़े हुए हैं. लिहाजा, इस दमघोंटू माहौल में काम करने के बजाय राज्य काडर के 137 में से आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों ने दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति की इच्छा जाहिर की है.

भाकपा और वालोमो के दूसरे साझीदारों की माकपा से नाराजगी के अपने सबब हैं. उनका दावा है कि सभी महत्वपूर्ण फाइलें, यहां तक कि भाकपा के नियंत्रण वाले मंत्रालयों से संबंधित फाइलें भी तिरुअनंतपुरम में माकपा मुख्यालय ए.के. गोपालन केंद्र से होकर गुजरती हैं. एक भाकपा मंत्री ने कहा, "सचिवालय में हर कोई इसे बहुत चलताऊ ढंग से ले रहा है क्योंकि नौकरशाहों को मालूम हो गया है कि किसी काम में कोई श्रेय मिलने वाला नहीं है." इस मंत्री की यह भी शिकायत है कि गैर-मार्क्सवादियों द्वारा नियंत्रित मंत्रालयों को धन मुहैया नहीं कराया जा रहा है.

मई में त्रिचुर जिले के ताड़ी निकालने वालों के महीने भर चले आंदोलन से माकपा के खिलाफ भाकपा का अंदरूनी गुस्सा फूट पड़ा. ताड़ी निकालने वालों को भाकपा की श्रमिक शाखा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) का समर्थन हासिल था. वे न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करने की मांग कर रहे थे. मार्क्सवादी आबकारी-मंत्री के.आर. गौरी ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया. इससे भाकपा के भीतर यह संदेह बढ़ने लगा कि माकपा अपनी मजदूर शाखा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) को बढ़ावा देना चाहती है. एटक नेताओं द्वारा गौरी की आलोचना शुरू किए जाने के बाद पूरे केरल में दोनों पार्टियों के समर्थक मजदूरों के बीच झड़पें शुरू हो गईं. हालांकि, अंततः समझौता तो हो गया, लेकिन भाकपा नेताओं ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा मंत्रिमंडल के कामकाज की आलोचना बंद नहीं की है.

कार्टून: अजीत नैनन

उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित हिंदू धर्मगुरुओं ने "मंदिरों के प्रशासन को 'नास्तिकों' से मुक्त कराने के लिए" आंदोलन छेड़ दिया है. उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादियों ने प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर का प्रशासन अपने कब्जे में ले लिया है.

लेकिन मुख्य लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है. पिछले कुछ हफ्तों में तिरुअनंतपुरम और उसके आसपास के इलाके माकपा और संघ कार्यकर्ताओं की झड़पों से हिल उठे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोनों संगठनों के बीच तनातनी पुरानी बात है. जब माकपा सत्ता में होती है तो हिंसा बढ़ जाती है. मार्क्सवादियों का दावा है कि संघ उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए इंका का काम कर रहा है.

और मार्क्सवादी ऐसा न होने देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं. उन्होंने अपनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए कमर कस ली है. माकपा के महासचिव ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद ने तो 'आत्मरक्षा' के लिए हथियार तक उठाने के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के अधिकार का बचाव किया है. जून के शुरू में एक प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "जब संघ और कांग्रेस (इ) के गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं तो हम अकेले पुलिस पर निर्भर नहीं कर सकते. हमें आत्मरक्षा का अधिकार है और जवाब में हम भी हमला कर सकते हैं." विपक्षी नेता और पूर्व इंका मुख्यमंत्री के. करुणाकरन ने कहा, "नंबूदिरीपाद ने इस तरह का बयान देकर पुलिस को खुलेआम चेतावनी दी है कि वह उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ न लगाए."

लेकिन यह विवाद माकपा पर अंकुश नहीं लगा सका. एक हफ्ते बाद कन्नानूर में पुलिस संघ के सातवें राज्य स्तरीय सम्मेलन में नयनार ने जोर देकर कहा, "पुलिस की भी अपनी राजनैतिक विचारधारा होनी चाहिए. इसके बिना वह असफल ही होगी. और वालोमो सरकार के बिना आप में न तो अपनी मांगें मनवाने की ताकत होगी और न ही अपनी कोई हैसियत." यह इस तथ्य को याद दिलाने के लिए कहा गया कि पुलिस संघ 1980-82 में नयनार मंत्रिमंडल के दौरान ही बना था. नयनार ने पुलिसवालों से अपील भी की कि वे उनकी सरकार की रक्षा करें.

नयनार के भाषण ने करुणाकरन को उन पर हमला करने के लिए पूरा मौका दे दिया. उन्होंने कहा, "नयनार का बयान संविधान का उल्लंघन है. किसी भी मुख्यमंत्री ने पुलिस का इस तरह राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं की थी." आलोचना विपक्ष ने ही नहीं की, वालोमो के एक भाकपा मंत्री ने भी कहा, "माकपा प्रशासन और पुलिस पर पार्टी का प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है."

भाकपा की निराशा तो साफ झलकती है. लेकिन करुणाकरन यह महसूस करते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकती. "वालोमो में शामिल भाकपा समेत सभी छोटी पार्टियां माकपा से भयभीत हैं. मार्क्सवादी उन पर जबरन रोब गांठते हैं." केरल के मार्क्सवादी आका नौकरशाही और पुलिस के साथ भी यही करते दिख रहे हैं.

—श्रीधर पिल्लै

लद्दाख

बर्फ की गरमी और तल्खी

अस्मिता पर खतरे के खिलाफ बौद्धों का आंदोलन तेज

लेह की सड़कों पर यह एक नया दृश्य था. लद्दाखी बौद्ध मठों में बजाए जाने वाले ढोल और तांबे की लंबी सुरणी, जो श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक वातावरण पैदा करने की भूमिका निभाते आए हैं, इस बार प्रदर्शनकारियों के लिए मानो रणभेरी बन गए थे. लेह के प्रमुख बौद्ध मंदिर चोखंग के बाहर एक ओर पीले और लाख वाले रंग के चोगों में सजे सैकड़ों लामा काफी ऊंची आवाज में नारे लगा रहे थे, दूसरी ओर महिलाओं का विशाल हुजूम था. और जिले के दूरदराज इलाकों से ग्रामीणों से भरकर आए चार ट्रकों से लोग उतर रहे थे.

प्रदर्शनकारियों के हाथों में लहराने वाली तख्तियों पर मोटे-मोटे शब्दों में इस तरह के नारे लिखे थे: 'कश्मीर सरकार लद्दाख में मानवाधिकारों का हनन कर रही है', 'बौद्धों पर अत्याचार, भेदभाव बंद करो.' आम तौर पर शांत मानी जाने वाली लद्दाखी जनता पिछले कुछ महीनों से अशांत है. उसकी इस अशांति का चरम बिंदु 14 जून को तब देखने को मिला जब प्रदेश के इस सबसे बड़े जिले में बंद का आयोजन किया गया और पांचों खंडों में जोरदार जुलूस निकाले गए. हालांकि अधिकांश लद्दाखियों की नाराजगी का मुख्य कारण ईसाई मिशनरियों से उनकी बौद्ध अस्मिता को होने वाला खतरा है पर वर्तमान आंदोलन को शह देने वाला असली मुद्दा स्थानीय संस्थाओं के साझे संगठन लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए) के चार युवा कार्यकर्ताओं की आतंकवाद निरोधक कानून के तहत की गई गिरफ्तारी है.

इन चार युवकों को एक स्थानीय ईसाई 25 वर्षीय प्रेम पॉल के घर बम रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है. पॉल ने 30 मार्च के दिन श्रीनगर की अदालत में एक 21 वर्षीया बौद्ध युवती यंग डोल के साथ विवाह कर लिया था जिसने चार दिन बाद ही ईसाई धर्म अपना लिया और उसका नया नाम एलिज़ाबेथ रख दिया गया. 6 मई की रात उनके घर में एक विस्फोट हुआ जिसमें कोई घायल तो नहीं हुआ पर रसोईघर की दीवार में एक छेद हो गया. दो दिन बाद स्थानीय मोरावियन चर्च के पादरी और पॉल के स्कूल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: भवान सिंह

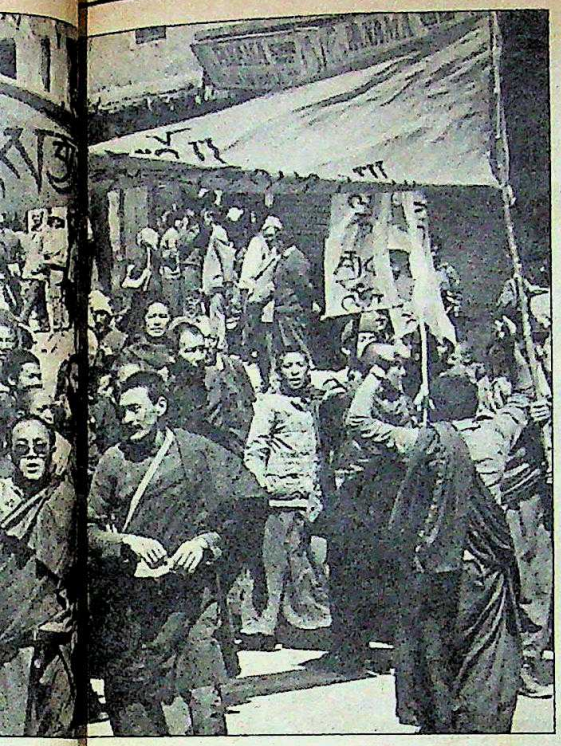

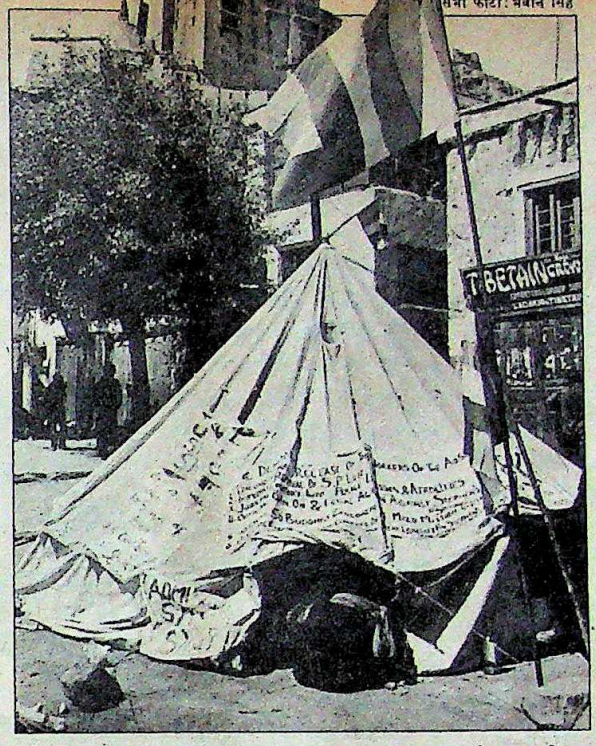

(ऊपर बाएं से) लामाओं का प्रदर्शन, और धरना; (नीचे) आंदोलन के नेता

के प्रिंसिपल स्टीफेन हीशे ने सरकार को एक कड़ा पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि कुछ बौद्ध युवकों के आतंकवाद के कारण ईसाई अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है. जिले की 68 हजार आबादी में ईसाइयों की संख्या 300 से भी कम है. बौद्धों का अनुपात 85 फीसदी है और शेष मुसलमान हैं. हीशे के पत्र का असर यह हुआ कि अधिकारियों ने तुरंत आतंकवाद विरोधी अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

इस पत्र के अलावा हीशे उनकी नाराजगी का केंद्र यीशु की जीवनी वाली अपनी एक पुस्तक के कारण भी बने हुए थे जिसके आवरण पर बौद्ध धर्म के खिलाफ टिप्पणियां छापी गई हैं. लिहाजा युवकों की रिहाई की मांग के साथ-साथ इस पुस्तक पर पाबंदी लगाने और श्रीनगर के एक मिशनरी स्कूल में रखे गए 52 बौद्ध विद्यार्थियों को वापस भेजे जाने की मांगें भी रख दी गईं.

इन मांगों के समर्थन में 10 मई को सड़कों पर जुलूस निकाले गए और प्रशासन ने सख्ती की. लामाओं को भी नहीं बख्शा गया. उनके धरने को तोड़ने के लिए पुलिस ने जोर-जबरदस्ती करने के बाद चोखांग के भीतर तक उनका पीछा किया. छह लामाओं को गिरफ्तार किया गया. इन सबसे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. तनाव को कम करने के लिए काफी प्रयास किए गए. वहां के प्रधान लामा कुशक बकुला जो कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं, प्रधानमंत्री से मिले. उसके बाद राज्य के राजस्व-मंत्री प्यारेलाल हंडू भी लेह गए. मई के अंत तक मुख्य-मंत्री फारूक अब्दुल्ला और स्थानीय सांसद व परिवहन उपमंत्री पी. नामग्याल ने भी लेह का दौरा किया. हंडू की यात्रा इस मायने में महत्व-पूर्ण रही कि स्थानीय मुस्लिम नेताओं की मध्य-स्थता से हुई बातचीत में बौद्धों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गईं.

पुस्तक के मामले में हीशे ने यह घोषणा की कि यह पुस्तक अब और वितरित नहीं की जाएगी. बौद्धों का कहना है कि हंडू ने यह आश्वासन भी दिया था कि श्रीनगर से स्कूली बच्चों को सरकारी खर्चे पर उनके घरों में वापस भेज दिया जाएगा. लेकिन जब ये वायदे पूरे नहीं हुए तो जून में आंदोलन ने नया रुख ले लिया.

लेह शहर में भले ही तनाव इस कारण रहा हो, पर ग्रामीण इलाकों में धार्मिक मुद्दा ही प्रमुख था. बौद्ध धर्म को खतरे की भावना वहां फैल रही है. स्थानीय स्तान्ना गोंपा के प्रमुख लामा और लद्दाखी गोंपा संघ के उपाध्यक्ष रिंपोछे नावांग तोन्योत दोरजी कहते हैं, "धर्म पर आए खतरे को देखकर अब वे लामा भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं जो पहले खुद को इससे परे रखे हुए थे."

सच तो यह है कि बौद्धों की असली शिकायत ईसाइयों से नहीं बल्कि मुसलमानों से है. एलबीए की राजनीति पर हाल ही में पकड़ जमाने वाली युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि जोरा राज्य सरकार की पक्षपाती और संकीर्ण धार्मिक नीतियों से एकदम नाराज हैं. बौद्धों का कहना है कि सरकार मुसलमानों को जमीन देने के मामले में तो बिलकुल देर नहीं लगाती लेकिन बौद्धों को इसके लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता है. मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में भी उनके अनुपात से कहीं अधिक स्थान मिलते हैं. उनका यह भी आरोप है कि पुलिस बौद्धों को लगातार परेशान व पीड़ित करती चली आ रही है. मुस्लिम बहुल कारगिल से भी उन्हें शिकायतें हैं जहां बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता और वहां का एकमात्र गोंपा भी खस्ता हालत में है. यहां तक कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सांसद नामग्याल भी मानते हैं कि, "साल-दर साल यहां आम समस्याओं का अंबार लगता चला जा रहा है."

इन पुरानी शिकायतों को लेकर लोगों द्वारा मैदान में उतरने के पीछे नवंबर 1986 में हुए राजीव-फारूक समझौते की भी खासी भूमिका है. यहां के बौद्ध परंपरा से ही कांग्रेस समर्थक रहे हैं. लेकिन अब नेशनल कान्फ्रेंस के साथ समझौते के बाद पार्टी स्थानीय समस्याओं से निबटने की अपनी परंपरागत भूमिका भी नहीं निभा पा रही. पार्टी के एक स्थानीय नेता निजी बातचीत में कहते हैं, "राजीव को तो इस इलाके की कोई चिंता ही नहीं है." सच तो यह है कि वर्तमान आंदोलन के कई नेता इंका कार्यकर्ता हैं. एलबीए महासचिव स्पाल्बार स्थानीय युवा इंका के अध्यक्ष हैं और मुख्य प्रवक्ता जोरा स्थानीय इंका के सह सचिव हैं.

इस राजनैतिक अलगाव में आतंकवाद के मुद्दे ने एक और मोड़ ला दिया है. सख्ती बरतने की वकालत करते हुए फारूक कहते हैं, "पंजाब में हमने ऐसा नहीं किया और अब हम उसका अंजाम भुगत रहे हैं." लेकिन इस तरह पंजाब के साथ तुलना करके उन्होंने आम लद्दाखियों को नाराज कर दिया है जो अब तक के युद्धों में अपने बलिदान और देशभक्ति पर गर्व करते हैं. एलबीए के नेता सेरिंग लाकरूक की आपत्ति है, "ये लोग हमें देश भर की नजरों में गिराना चाहते हैं." यह प्रतिक्रिया भले ही तीखी हो पर यह स्पष्ट है कि इस इलाके के साथ हुई ज्यादतियों ने ही इस आंदोलन को जन्म दिया है. —**डेविड देवदास** लेह में

कश्मीर

घाटी में असंतोष

फारूक हिले आंदोलनों से

गरमी बढ़ते जाने के साथ ही कश्मीर का राजनैतिक माहौल भी गरमा गया है. मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कई आंदोलनों से घिर गए हैं. बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध में 10 जून को सारा श्रीनगर बंद रहा. शहर के खानियार से लेकर घनी आबादी वाले बोहड़ी कदल और जैना कदल तक के पूरे तीन वर्ग किलोमीटर इलाके में बंद ने हिंसात्मक शक्ल अख्तियार कर ली. पत्थरों और देसी पेट्रोल बमों से लैस युवा प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हुई. जवाब में उन पर आंसू गैस छोड़ी गई और गोलियां बरसाई गईं. इस हिंसक मुठभेड़ में एक पुलिसवाला रतन लाल मारा गया और तीन लोग पुलिस की गोलियों के शिकार हुए.

अगले हफ्ते भी इलाके में हिंसा की छिटपुट वारदातें होती रहीं, हालांकि घाटी के बाकी हिस्सों में शांति रही. पर राजनैतिक शांति भंग हो चुकी थी. फारूक ने इसके लिए अपने पूर्व चुनाव सहयोगी मीरवायज़ फारूक को जिम्मेदार ठहराया, "उनके प्रभाव वाले इलाकों को छोड़कर कहीं कोई समस्या नहीं है. यह आग उन्हीं की लगाई हुई है." मीरवायज़ ने आरोप का खंडन करते हुए कहा, "सरकार को गिराने की साजिश रचने वाला मैं आखिरी शख्स होऊंगा." उधर इलाके के नौजवानों में दोनों नेताओं के प्रति तिरस्कार का भाव उपजा है. वे उन पर पैसे और सत्ता के पीछे भागने का आरोप लगाते हैं. कश्मीरी नेताओं के बारे में कहा जाने लगा है कि वे 'सब चोर हैं.'

नेशनल कान्फ्रेंस-इंका गठजोड़ की सरकार के खिलाफ बढ़ रहे इस असंतोष की वजह से ही इन गर्मियों में पूरी घाटी में कई आंदोलन उठ खड़े हुए. हालांकि खूनखराबा एक गरीब और घनी आबादी वाले उस इलाके तक ही सीमित रहा जहां हिंसा अक्सर ही होती रही है. पर घाटी के बाकी हिस्सों में भी कई शांतिपूर्ण आंदोलन हुए.

विपक्षी नेता अब्दुल गनी लोन के मुताबिक बिजली की दरों में वृद्धि ने 'पलीता सुलगाने का काम किया'. पिछली सर्दियों में बिजली की सप्लाई खास तौर पर खराब रही. कुछ इलाकों में तो बिजली हफ्ते में एक बार चंद घंटों के लिए ही दी जाती रही. इसलिए आश्चर्य नहीं कि जब सरकार ने 53 करोड़ रु. का बजट घाटा पूरा करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला किया तो लोग भड़क उठे.

पर उत्तेजना की यही एक वजह नहीं थी. एक महीना पहले सरकार ने बिक्री कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया. वर्षों से बिक्री कर की 30 करोड़ रु. की रकम व्यापारियों की ओर बकाया चली आ रही थी. केंद्र ने इस पर सख्त कदम उठाने के आदेश दिए. ऐसा होते ही व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई.

'मांस के संकट' ने तो और भी कहर ढाया. उन मांस विक्रेताओं का, जो अपने माल की कीमत 26 रु. से बढ़ाकर 32 रु. प्रति किलो करना चाहते थे, बहिष्कार करने

फोटो: मेहराजुद्दीन

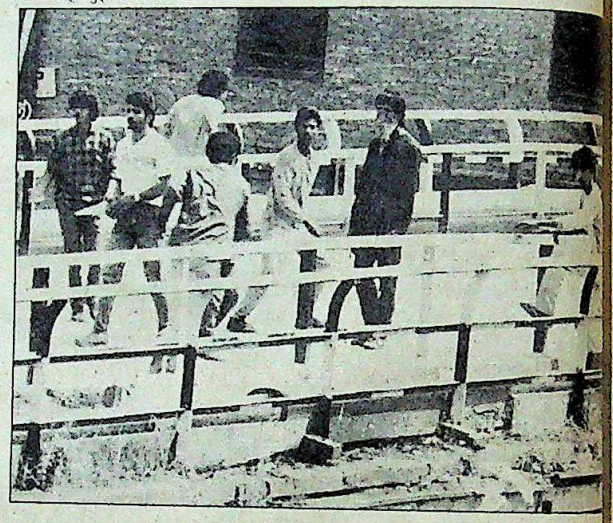

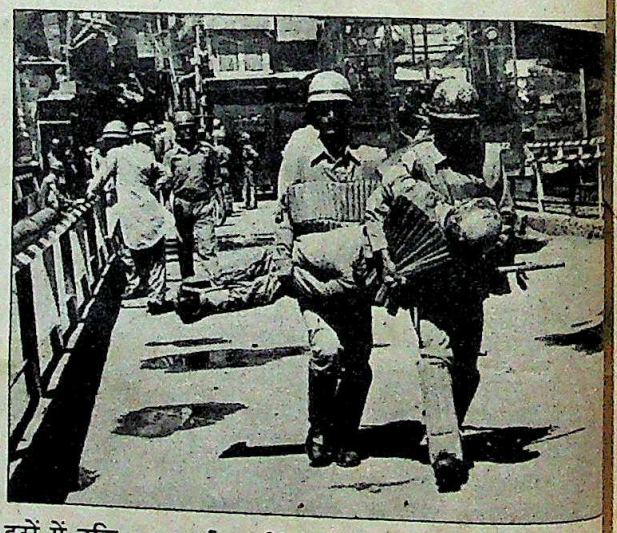

प्रदर्शनकारी (ऊपर) और एक घायल पुलिसवाला: बदले तेवर

की अगुआई करने के बाद फारूक ने पिछले महीने एकाएक ही उनकी मांग के आगे घुटने टेक दिए. इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई. श्रीनगर के एक निवासी कहते हैं, "पहले तो फारूक की अपील पर हमने दो महीने तक मांस छुआ नहीं. अब वे हमसे इसके मनमाने दाम दिलवाना चाहते हैं. मांस यहां कोई एय्याशी की चीज नहीं; यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारा मुख्य भोजन है." एक के बाद दूसरा आंदोलन खड़ा होने लगा. पिछले महीने हाईस्कूल के शिक्षकों ने हड़ताल कर दी. कृषि विभाग का भी काम ठप पड़ गया फारूक कहते हैं, "बदकिस्मती से सारे मसले एक साथ ही पैदा हो गए."

पर कोई भी राजनैतिक पार्टी इस असंतोष को भुनाने की स्थिति में नहीं थी. श्रीनगर से नेशनल कान्फ्रेंस सांसद अब्दुल रशीद काबुली कहते हैं, "इस समय पूरी तरह राजनैतिक शून्य पैदा हो गया है." लेकिन लोगों में उत्तेजना फैलने के साथ राजनैतिक गतिविधियों में भी तेजी दिखने लगी. पिछले महीने विपक्षी गठजोड़ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उसके प्रमुख भागीदार जमाते इस्लामी और स्टुडेंट्स इस्लामिक लीग के निकल जाने से दोफाड़ हो गया. फ्रंट के संयोजक मुहम्मद अब्बास अंसारी कहते हैं कि बाकी बचा संगठन अब कश्मीर के विलय का सवाल छोड़ देगा और वृहत्तर राजनैतिक गठजोड़ की दिशा में काम करेगा. फ्रंट के कई नेता मीरवायज से हाथ मिलाने की उम्मीद में हैं.

दूसरी तरफ प्रदेश इंका के पूर्व अध्यक्ष मुफ्ती मुहम्मद सईद की ताकत जनमोर्चा में शामिल होने के बाद बढ़ी है. राजीव गांधी और फारूक का विरोध करने की वजह से उनका रुतबा ऊंचा हुआ है. बहुत से इंकाई असंतुष्ट शायद अब मोर्चे में शामिल हो जाएं. पिछले पखवाड़े इंका महासचिव शीला कौल ने अप्रत्याशित घोषणा करके पार्टी के बहुत से ओहदों पर कम अहमियत वाले नेताओं को बैठा दिया था. यहां तक कि प्रदेश इंका अध्यक्ष गुलाम रसूल कार भी मानते हैं कि "इससे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई है."

बहरहाल, जैसे भी गठजोड़ बनें या बिगड़ें, बहुत कम लोगों को उम्मीद है कि जब तक फारूक को प्रधानमंत्री राजीव गांधी का विश्वास हासिल है, सरकार में तब्दीली के कोई आसार नहीं. मीरवायज कहते भी हैं, "अब वे सोचते हैं कि मुझे लोगों, अखबारों की क्या परवाह, राजीव साथ हैं तो सब कुछ ठीक है." उधर फारूक यह दलील देते हैं कि "केंद्र के सहयोग के बिना कोई राज्य नहीं चल सकता." जाहिर है उन्हें गद्दी पर बने रहने के लिए केंद्र पर अपनी निर्भरता का एहसास है. लेकिन जल्द ही उन्हें इस सवाल से भी जूझना पड़ सकता है कि अगर राजनैतिक प्रक्रिया पर से लोगों का भरोसा इस तरह उठता गया तो क्या वे अपने मौजूदा पद पर रह सकते हैं?

—**डेविड देवदास** श्रीनगर में

आंध्र प्रदेश

जान आफत में

बाबजी कांड में नया मोड़

नित नए नाटकीय जलवे दिखाने के चक्कर में नंदमूरि तारक रामराव को लेने के देने पड़ सकते हैं. चार साल पहले हैदराबाद में उन पर हमला करने वाले नौजवान मल्लेला बाबजी की मौत की जांच में अब तक जो कुछ सामने आया है उससे तो यही लगता है. यह जांच राज्य सरकार के हुक्म से हो रही है. पुलिस ने बाबजी के कमरे से जो दो चिट्ठियां बरामद कीं उनके जगजाहिर कर दिए जाने से यह मामला सनसनीखेज हो उठा है.

बाबजी के खतों की जांच-पड़ताल के नतीजे मुख्यमंत्री रामराव के लिए भारी पड़ सकते हैं

नागेंद्र राव

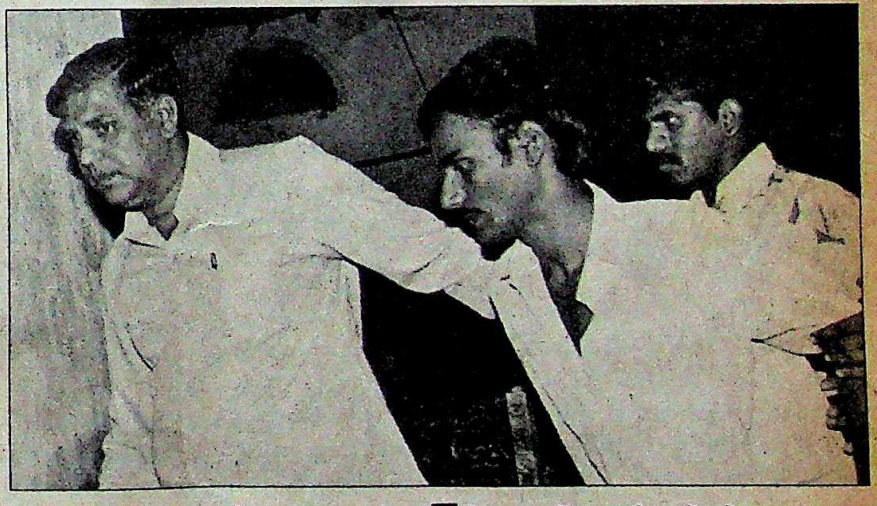

हिरासत में बाबजी: चौंकाने वाला दावा

एक खत में लिखा है कि 9 जनवरी 1984 को हुआ हमला रामराव के दिमाग की उपज था. यह नाटक जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए किया गया. रामराव अपने इस 22 वर्षीय स्वयंभू प्रशंसक के हमले में बच तो गए पर उनके अंगूठे पर दो सें.मी. लंबा जख्म हो गया. हमले के वक्त वे हैदराबाद के लालबहादुर शास्त्री स्टेडियम में तेलुगु देशम सरकार की पहली सालगिरह पर चल रहे कार्यक्रम देख रहे थे.

बाबजी ने अपने एक खत में लिखा है कि हमले का नाटक करने के लिए उसे 3 लाख रु. देने का वायदा किया गया था लेकिन दिए गए सिर्फ 30,000 रुपए. खत में यह भी लिखा था कि पूरी योजना मुख्यमंत्री और उनके दामाद चंद्र बाबू नायडू ने तैयार की. खत के मुताबिक हमले में जख्म हुआ, यह दिखाने के लिए रामराव ने अपना अंगूठा पहले ही काट लिया था.

लेकिन पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट टी.बी. बनर्जी द्वारा ये खत बरामद करने के बाद दबा दिए गए थे क्योंकि बाबजी के मामले में रामराव, नायडू और पूर्व गुप्तचर प्रमुख के. विजयराम राव सरीखी हस्तियों के नाम सामने आ रहे थे और वे इस मामले में फंस सकते थे. बाबजी पिछले साल 30 नवंबर को श्री दुर्गा लॉज के 14 नं. कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया था.

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश 62 वर्षीय चितला श्रीरामुलु ने 11 जून को ये खत जगजाहिर कर दिए. उन्हें राज्य सरकार ने तीन महीने पहले बाबजी की मौत की जांच

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए नियुक्त किया था और मजिस्ट्रेट बनर्जी ने खत इसी सिलसिले में उन्हें सौंप दिए थे. दूसरा खत आत्महत्या से पहले के बयान सरीखा है. इसमें बाबजी ने अपने माता-पिता को परेशानियों में डालने के लिए उनसे माफी मांगी है. उसने यह भी लिखा है कि हमले और उसकी योजना बनाने की समूची जिम्मेवारी खुद पर लेने संबंधी विजयराम राव के सामने दिया गया उसका इकबालिया बयान भी तयशुदा योजना का ही एक हिस्सा था. इस रहस्योद्घाटन के बाद इंका ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की माँग की. मगर रामराव अविचलित रहे.

जब यह बवाल उठा मुख्यमंत्री दूसरे प्रांतों में उपचुनावों के प्रचार अभियान में व्यस्त थे. इसलिए उनके बचाव का मोर्चा राज्य के मंत्रियों ने संभाला. वनमंत्री जी. मुद्दुकृष्णनमा नायडू का कहना था कि बाबजी की मौत जिस लॉज में हुई वह इंका से सहानुभूति रखने वाले एक शख्स की है. तेलुगु देशम के तीन मंत्रियों और दो विधायकों ने कहा कि बाबजी से ये खत दबाव में लिखवाए गए क्योंकि "इनकी भाषा किसी कानूनदां की भाषा लगती है."

आरोपों के खंडन से मामला और उलझ गया. दरअसल बाबजी का मुकदमा बड़ी तेजी से निपटाया गया था. खुद रामराव अदालत में हाजिर हुए और न्यायाधीश से अपील की कि "वे बाबजी के प्रति नरम रुख अपनाएं और उसे माफ कर दें." अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सजा की अवधि उसके हिरासत में रहने की अवधि में समायोजित कर दी. न्यायाधीश ने फैसले में लिखा, "आरोपी का इरादा मुख्यमंत्री को शारीरिक क्षति पहुंचाने का नहीं था."

श्रीरामुलु का काम आसान नहीं है. हालांकि जांच-पड़ताल की तीन महीने की मियाद 21 जून को खत्म हो गई. लेकिन न्यायाधीश को इस साल के आखिर तक का वक्त मिल गया है. मामले की तह तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले पता लगाना होगा कि क्या ये खत हकीकत में बाबजी ने ही लिखे. इन खतों की लिखावट की जांच बाबजी के घर पर मिले नमूनों से की गई है. श्रीरामुलु ने हस्तलिपि विशेषज्ञों से कहा है कि वे हैदराबाद न्यायालय और बाबजी की नौकरी करने की जगहों पर उपलब्ध उसकी लिखावट के नमूने इन खतों की लिखावट से मिलाएं. लेकिन जांच-पड़ताल की कार्रवाई जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी अपने आप को इस सबसे उदासीन दिखाने के बावजूद रामराव की जान सांसत में ही अटकी रहेगी.

—अमरनाथ के.मेनन

बिहार

जघन्य हत्याकांड

जातिवादी जुनून का नतीजा

मध्य बिहार के कुछ जिलों पर उग्रवाद का जो असर है उससे तो लगता है कि शांति की तमाम कोशिशें नाकाम ही होती रहेंगी. पिछले पखवाड़े जहानाबाद जिले में एक-दूसरे से एक किलोमीटर दूर बसे दो गांवों नोनहीगढ़-भागलपुर टोला और नगवां में दो बच्चों समेत 19 हरिजनों की जिस निर्दयता से हत्या कर दी गई उससे समूचा राज्य प्रशासन ही हिल गया. और तो और, प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्थिति का जायजा लेने के केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिंतामणि पाणिग्रही को मौका-ए-वारदात पर भेजना पड़ा.

सभी फोटो: कृष्ण मुरारी किशन

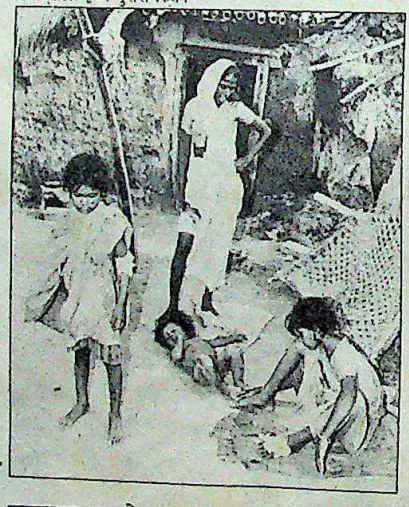

तकरीबन 50 हथियारबंद हमलावर 16 जून की रात नोनही में घुसे और सात घरों के सभी मर्दों को खत्म कर दिया. सात औरतें गोली लगने से घायल हो गईं और दो बच्चे—छह महीने की पिंकी और चार साल का उमेश मोची—अपने पिता 35 वर्षीय लाल दास पवन के साथ जान से हाथ धो बैठे. दस मिनट बाद हत्यारे नगवां की ओर रवाना हो गए और वहां उन्होंने दो हरिजन युवकों— 17 वर्षीय रवींद्र मोची और 25 वर्षीय कारू मोची— को गोलियों से भून दिया और चार लोगों को घायल कर दिया. इसके बाद वे चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए.

विडंबना तो यह है कि दोनों गांवों के आसपास दो दबंग जातियों— यादव और भूमिहार— के लोग रहते थे, पर हमलावरों को चुनौती देने की आवाज किसी की अंतरात्मा ने नहीं दी. पर आजाद और राज्य के अधिकारी इस तर्क को नहीं मानते. कमजोर तबके के लोगों की जिंदगी न बचा पाने के लिए आजाद ने स्थानीय जमींदारों की आलोचना भी की है. उन्होंने जिला प्रशासन को सभी बंदूकों के लाइसेंस जब्त करने और जमींदारों पर सामूहिक जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. इससे स्थानीय राजनीतिक चिंतित हो उठे हैं.

हालांकि मध्य बिहार के जिलों में पहले भी नरसंहार हुए हैं, पर इस बार हत्यारों की मंशा कोई नहीं समझ पा रहा है. हत्यारों को पहचानना तो दूर की बात है. जहानाबाद के जिला मजिस्ट्रेट एच.सी. सिरोही तक ने इसकी उम्मीद नहीं की थी. अरवल नरसंहार के बाद से वे इस इलाके की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को लगातार सुधारने में लगे हुए हैं.

नरसंहार के शिकार (दाएं); और जो बच गए (बाएं): रहस्यमय हत्याकांड

वैसे तो 933 गांवों वाले जहानाबाद जिले (आबादी 12 लाख) को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है पर इन दोनों गांवों में न तो कभी हिंसा हुई और न ही इनमें जमींदारों-भूमिहीनों के संघर्ष की कोई खबर है. नगवां में मारे गए रवींद्र की मां सुमित्रा कहती हैं, "जब हम किसी जमींदार के यहां काम ही नहीं करते हैं तो किसी के साथ झगड़ा कैसे हो सकता है?" उसके परिवार के लोग दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं.

लेकिन 30 वर्षीया मालती एक अलग ही कहानी कहती हैं. इस हत्याकांड में उनके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

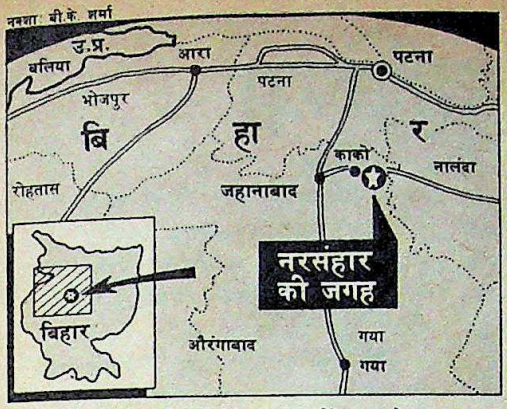

पति और दो बच्चे मारे गए. उन्हें खुद पैर व छाती के नीचे गोली लगी है. उनके परिवार ने एक भूमिहार जमींदार राजेंद्र सिंह से बटाई पर जमीन और 1,000 रुपए कर्ज लिए थे. कर्ज के पैसे को लेकर झगड़ा होने के बाद राजेंद्र ने सारा गेहूं उठवा लिया था. मालती कहती हैं कि नरसंहार शायद इसी झगड़े की वजह से हुआ हो.

दूसरी ओर उनके पड़ोसियों का कहना है कि नोनही और नगवां के बाकी हरिजनों की तरह मालती भी अति वामपंथी संगठन इंडियन पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) की सक्रिय कार्यकर्ता हैं. वे कहते हैं कि जहानाबाद और पटना के देहाती इलाकों में आईपीएफ और दूसरे नक्सलवादी संगठनों के बीच लगातार बढ़ रहा टकराव ही इस नरसंहार की वजह है.

आईपीएफ कई वर्षों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआईएमएल) के दो संगठनों—मजदूर किसान संग्राम समिति (मकिसंस) और बिहार प्रदेश किसान सभा (बिप्रकिस)—के साथ मिलकर जमींदारों द्वारा भूमिहीनों के शोषण के खिलाफ भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर रहा है. पर हाल ही में इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए आईपीएफ ने 'मकिसंस' से भिड़ना शुरू कर दिया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक अक्तूबर से यह लड़ाई तेज हो गई है और तबसे आपसी मुठभेड़ों की 30 वारदातों में 50 लोगों की जान जा चुकी है. हालांकि दोनों गुटों के नेताओं ने आपस में मिलकर इस द्वंद्व को दूर करने की कोशिश की है ताकि जमींदारों और पुलिस की चुनौती का जवाब मिलकर दिया जा सके, पर वे अपने कार्यकर्ताओं का मेल करा पाने में नाकामयाब रहे हैं. उधर 'मकिसंस' का 'बिप्रकिस' से झगड़ा चल रहा है और इस वजह से मामला और गड़बड़ा गया है. पटना जिले के पालीगंज में जब दोनों संगठनों ने एक-दूसरे के एक एक सदस्य का अपहरण कर लिया तो उसके बाद आईपीएफ के दो व 'मकिसंस' के तीन लोग जान गवां बैठे.

स्थानीय लोग तो इस नरसंहार की वजह इन उग्रवादी संगठनों के आपसी संघर्ष को बता रहे हैं पर तीनों गुटों के नेता इससे इनकार कर रहे हैं. इस इनकार के बावजूद कई वारदातें हुई हैं जिनमें इन संगठनों की भूमिका दिखती है.

27 मार्च को खालिसपुर गांव में डकैत हरेराम यादव के गिरोह ने 'बिप्रकिस' के सदस्य मेघनाथ महतो की हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि यह गिरोह 'मकिसंस' से संबंध रखता है. उक्त हत्या के एक हफ्ते बाद गांव पर हमला बोलकर कुछ औरतों की बेइज्जती की गई. कोई भी पुलिस कार्रवाई न होने पर गांववालों ने जिला कलक्टर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया. उस दिन हरेराम गिरोह के रामजी यादव और 'मकिसंस' के एक संदिग्ध कार्यकर्ता को मौका-ए-वारदात पर देखा गया था. बाद में इन लोगों की पत्थर मार-मारकर हत्या कर दी गई.

इसके इस हत्या बाद बदला लेने के लिए हरेराम गिरोह ने आईपीएफ और 'बिप्रकिस' के कुछ लोगों की हत्या कर दी. आतंक इस कदर फैला कि गांववाले खालिसपुर को खाली करके चले गए. स्थानीय लोगों को शक है कि इनमें से कुछ लोगों ने नोनही में शरण ली और इसी वजह से यह ताजा नरसंहार हुआ.

कई घटनाएं इस कदर गुत्थमगुत्था हैं कि स्थानीय प्रशासन के लिए पूरा मामला टेढ़ी खीर बन गया है. सिरोही कहते हैं, "अपराधियों के चरित्र और उनकी मंशा के बारे में कई संदेह हैं और फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता." उधर मालती का बयान राज्य में जमींदारों और भूमिहीनों के पुराने संघर्ष के ताजा चरित्र का संकेत देता है.

इस बीच केंद्र सरकार ने बिहार में उग्रवाद की समस्या की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय में एक अलग प्रकोष्ठ बना दिया है. लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक सामाजिक-आर्थिक योजनाएं प्रभावी ढंग से नहीं लागू की जाएंगी तब तक बिहार की स्थिति में बहुत सुधार नहीं होने वाला.

और जो कुछ हो, नई वारदात से साफ है कि आने वाले दिन चार महीने पहले सत्ता में आए मुख्यमंत्री आजाद की कड़ी परीक्षा ही लेंगे.

—फरजंद अहमद, जहानाबाद में

आपकी चहेती पत्रिका
आपके दरवाज़े पर
न खरीदने का झंझट...
न खत्म होने का डर

इस सुविधा का लाभ उठाइए.
आपनी चहेती इंडिया टुडे
घर बैठे – नियमित पाइए.
न खरीदने जाने की ज़रूरत...
न अंक खत्म होने का डर,
इंडिया टुडे
समय से पहुंच जाए आपके घर!
बस कूपन भर कर भेज दीजिए,
देर मत कीजिए !

नाम _____
डाक पता : _____

मूल्य : वार्षिक रु. 120/-
भुगतान का माध्यम -- चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट
कृपया चैक निम्नलिखित नाम पर बनाए और इस पते पर भेजें
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट थौमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. नं. 69, दिल्ली मथुरा रोड,
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

MILESTONES/IT/120

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाश्ता...और नज़रिया

आपके पास और कुछ हो न हो, उसका होना निहायत जरूरी है. उसके बिना आपकी पहचान ही नहीं बन सकती कि आप भी कोई हस्ती हैं. जाहिर है अब तक उस चीज का नाम आपके जेहन में आ गया होगा. हां, वही 'स्टेटस सिंबल'—यानी हैसियत का प्रतीक!

जमाने और जगह के हिसाब से ये प्रतीक बदलते रहते हैं. आजकल दिल्ली में हालत यह है कि आप राजीव गांधी के साथ नाश्ता कर लें तो बस यह हो गया आपके लिए स्टेटस सिंबल.

राजीव गांधी पिछले कई दिनों से समाज के हर तबके के लोगों जैसे किसानों, मजदूर नेताओं, नगर नियोजकों और भी कई दूसरे विशेषज्ञों से गपशप करने के लिए, उनके विचार जानने के लिए उन्हें अपने यहां नाश्ते पर बुलाते रहे हैं. इन जमावड़ों में जाहिर है बुद्धिजीवी और संपादक रहेंगे ही. इसलिए जिन लोगों को इन नाश्तों पर आमंत्रित नहीं किया जाता वे बस सोचते ही रहते हैं कि आखिर यह चक्कर है क्या.

तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक दिन मैं राजीव गांधी के एक सहायक से पूछ ही बैठा, "क्या आप मानते हैं कि विशेषज्ञों के साथ नाश्ता और चर्चा करने भर से प्रधानमंत्री की ज्ञानवृद्धि हो जाती होगी?"

वह सहायक मेरे इस सीधे सवाल पर कुछ चकित हो गया. उसने कुछ झल्लाते हुए कहा, "माफ कीजिए आपको गलत-फहमी हुई है. राजीव जी उन विशेषज्ञों से अपनी ज्ञानवृद्धि नहीं करते, बल्कि उन्हें तो उन विशेषज्ञों की ज्ञानवृद्धि करनी होती है और यही काम वे इन नाश्ता बैठकों में करते हैं."

मैंने आश्चर्य से पूछा, "भला विशेषज्ञों को वे किस तरह शिक्षित करते हैं?"

सहायक ने आश्वस्त करते हुए मुझसे कहा, "मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे विशेषज्ञ से कराऊंगा जो राजीव जी के साथ नाश्ता कर चुका हो. तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि मामला क्या है."

और मैंने प्रधानमंत्री के तीखे आलोचक रहे ख्यातिनाम संपादक से मुलाकात की. मैंने देखा वे अपनी घूमने वाली कुर्सी में धंसे, मुंह में दबी पाइप में बड़े मनोयोग से तंबाकू भरते, कश लगाते और फिर खिड़की से पार शून्य में घूरने लगते. मैंने उनसे कहा, "मुझे पता चला है कि आप प्रधानमंत्री के साथ उस नाश्ते में शरीक थे जिसमें कुछ कृषि विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए थे."

संपादक महोदय ने तत्काल जवाब दिया, "जी हां, मैं प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते में तब भी शरीक था जब योजना विशेषज्ञ आमंत्रित थे, तब भी जब मजदूर संघों के विशेषज्ञ आमंत्रित थे या दूरदर्शन के विशेषज्ञ आमंत्रित थे. ऐसे हर मौके पर प्रधानमंत्री मुझे बुलाना नहीं भूलते."

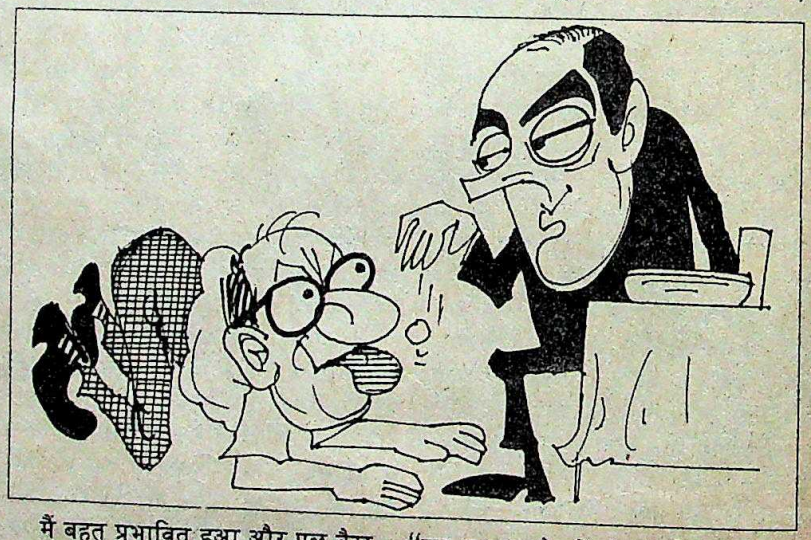

मैं बहुत प्रभावित हुआ और पूछ बैठा, "इतनी महत्वपूर्ण बैठकों में आप शरीक रहे तो बताइए कि आप प्रधानमंत्री से कितने प्रभावित हुए. मेरा मतबल आपके विचारों से है. उनके बारे में आपका नजरिया जरूर बदला होगा?"

मेरी उत्सुकता देखकर वे हंसते हुए बोले, "आपको इतना तो समझना चाहिए कि मेरे जैसे अनुभवी लोग किसी के साथ नाश्ते पर चर्चा करके ही अपने विचार नहीं बदल लेते."

"नहीं, कतई नहीं," मैंने जवाब दिया, "यानी आप अभी भी मानते हैं कि राजीव कच्चे ही हैं जैसा कि आपने अपने अखबार में पिछले साल लिखा था."

"बिलकुल सही समझा आपने," वे खुश होकर बोले, "मैं अब भी मानता हूं कि ऊपर से तो वे कच्चे दिखते हैं लेकिन भीतर से बड़े तिकड़मी हैं."

मैंने उन्हें याद दिलाया, "आपने यह भी लिखा था कि वे बड़े तुनकमिजाज हैं."

वे तपाक से बोले, "जी हां और मैं उस पर कायम हूं. राजीव तुनकमिजाज हैं. उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और तीखी होती है. उन्होंने कइयों को मूर्ख बनाया है लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सके."

फिर मैंने उन्हें बताया, "आपने उन पर फिजूलखर्ची और विलासिता को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए थे. क्या आप अब भी यही मानते हैं?"

संपादक महोदय गंभीरता से बोले, "इन नाश्ता बैठकों ने तो यही साबित किया है. राजीव अपने मेहमानों को तो पेट भर खाने को कहते हैं लेकिन खुद रूसी केवियर, तुर्क अंजीर और डच पनीर टुंगते रहते हैं. खुद इतनी सादगी से रहने वाला दूसरों को विलासिता के लिए प्रेरित करे यह आश्चर्य ही है."

मैंने गुस्से से कहा, "लेकिन आपने ही तो कहा था कि राजीव गांधी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी. अब क्या कहना है आपका?"

उन्होंने जोर देकर कहा, "आज भी मैं यही कहता हूं. एक दिन आएगा जब प्रियंका उनकी गद्दी पर बैठेंगी...."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पेश है

एल जी 600 पर्याप्त बिजली - सही दाम

नयी भेंट, बिड़ला यामाहा परिवार की।
जिन्होंने खासतौर पर
भारतीय परिस्थितियों के लिए बनाए
सही दाम वाले जेनरेटर।

बिड़ला यामाहा। जिन्होने भारत में पहली बार बनाए विश्व स्तर के पोर्टेबल जेनरेटर। वही आपके लिए पहले-पहल लाए हैं - एल जी 600। सुगठित और ईंधन कुशल जेनरेटर, जो आपको दे पूरी बिजली - बिल्कुल सही दाम पर!

इसे मिलाकर बिड़ला यामाहा आपको देते हैं सबसे ज़्यादा किस्म के, सही दाम वाले पोर्टेबल जेनरेटर। अब चुनिए उसे जो पूरी करे आपकी ज़रूरत।

विभिन्न जेनरेटर और उनकी क्षमता	उपकरण और उनकी अनुमानित वॉटेज
एल जी 600 400 वीए	रेफ्रिजरेटर 280 वॉट, बल्ब 60 वॉट, ड्रिल 350 वॉट
एल जी 900 650 वीए	डेजर्ट कूलर 600 वॉट, पंखा 70 वॉट, मिक्सर 475 वॉट
एल जी 900 ए सी* 650 वीए	पेट्रोल पम्प 1500 वॉट, फोटो कॉपियर 725 वॉट, टी वी 110 वॉट
एल जी 2000 1400 वीए	ट्यूब लाइट 45 वॉट, इलैक्ट्रिक टाइपराइटर 140 वॉट
एल जी 2800 2000 वीए	वी सी आर 45 वॉट, वॉटर कूलर 375 वॉट
* इसमें डी.सी. आउटपुट नहीं है	एक्स-रे मशीन 100 वॉट, एयर कंडिशनर 1250 वॉट

अपनी जरूरत का जेनरेटर चुनने के लिए इस तालिका की मदद लीजिए। यहां अनुमानित वॉटेज दी गई है। अधिक विवरण के लिए हमारे अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क कीजिए।

मार्केटिंग डिविजन
बिड़ला यामाहा लिमिटेड
ए-7, साउथ एक्सटेंशन भाग-1, रिंग रोड,
नई दिल्ली-110049

अब रु. 7,600 से उपलब्ध

Sista's-BYL-15-88 HIN E

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

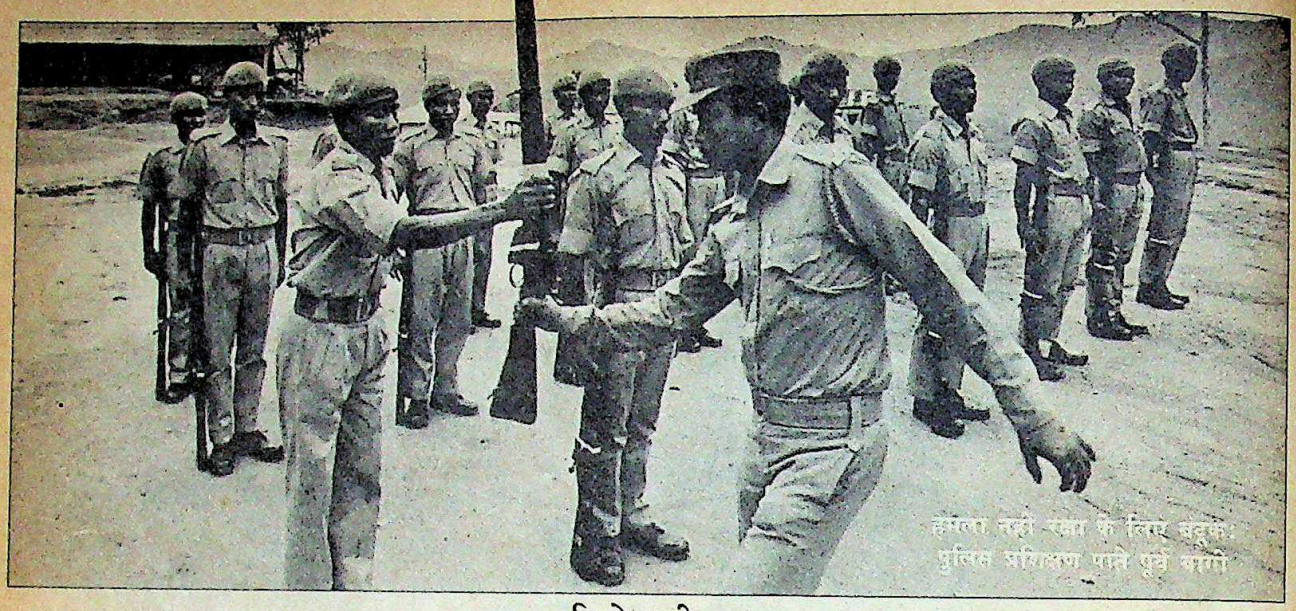

मिजो बागी

जीवन को मिला नया मकसद

समझौते के बाद हथियार डाल चुके बागी सामान्य जीवन से खुश

ललडेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के उनके हजारों बागी साथियों ने 'आजाद मिजोरम' का अपना सपना सच करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ करीब 20 साल तक संघर्ष किया. लेकिन 30 जून 1986 को ललडेंगा के साथ हुए मिजोरम समझौते के बाद हालात ने एकदम पलटा खाया. ललडेंगा एमएनएफ सरकार के मुख्यमंत्री के बतौर राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं. एमएनएफ के उनके 580 बागी साथी अब सामान्य स्थिति बहाल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं. लेकिन नई परिस्थितियों में एमएनएफ बागी किस तरह निर्वाह कर रहे हैं, नागरिक जीवन उन्हें कितना रास आ रहा है, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए वरिष्ठ संवाददाता **रमेश मेनन** *ने राज्य का दौरा किया और कई पुराने बागियों से बातचीत की. उनकी रिपोर्ट:—*

आइजोल के बाहरी इलाके में बने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में नए भर्ती रंगरूटों की एक टोली कदमताल में जुटी है. लकदक खाकी वर्दी में सजे इन सारे रंगरूटों के चेहरे एक जैसे ही दिखते हैं. लेकिन इनमें से 55 रंगरूट बाकी रंगरूटों से बिलकुल अलग हैं, या कभी थे. जून 1986 में मिजोरम समझौता होने के बाद एमएनएफ के इन बागियों ने हथियार डाल दिए. और अब उन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंसशुदा बंदूकें थाम ली हैं.

शुरू में उन्हें इस नई जिंदगी से तालमेल बैठाने में परेशानियां आईं. इस साल की शुरुआत में जब उन्हें भर्ती किया गया था तो उस वक्त उन्होंने अपने लिए विशेष नियमों की मांग की थी. मसलन उनमें से कोई भी

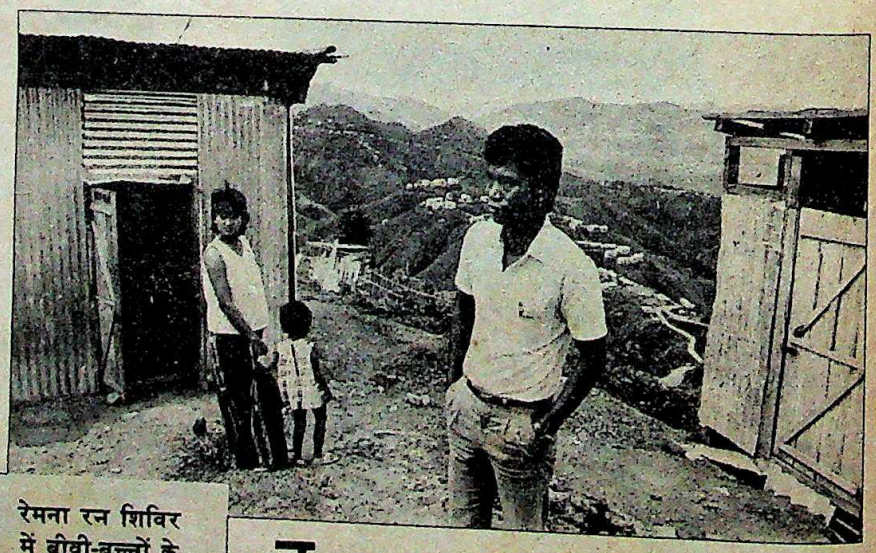

रेमना रन शिविर में बीवी-बच्चों के साथ डॉ. थंगदाइलोवा: ऊंचे इरादे

हमने अपने आपको कभी बहिष्कृत महसूस नहीं किया क्योंकि हमें पूरी इज्जत मिली''

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कठिन प्रशिक्षण जरूरी नहीं मानता था, क्योंकि उनके मुताबिक बगावत के दिनों में वे पर्याप्त प्रशिक्षण पा चुके थे, खासकर हथियारों के इस्तेमाल का. एमएनएफ के दूसरे बागियों की तरह उन्होंने भी लंबे बाल रखे थे और इन्हें कटाने को वे तैयार नहीं थे.

लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कायदे-कानूनों में छूट देने से इनकार कर दिया. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) दोथंगा कहते हैं, "हमें उनमें अनुशासन की भावना जगानी थी." हरेक रंगरूट को हर महीने 1,130 रुपए वेतन मिलता है. दस साल भूमिगत रहे एक रंगरूट 30 वर्षीय ललज़ौवा कहते हैं, "जंगल में तो हमने अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा नहीं था. लेकिन अब सोच सकते हैं क्योंकि हम अब कमा रहे हैं." ललज़ौवा अब एकदम बदल गए हैं. कुछ साल पहले भारतीय सेना के एक शिविर पर हमला करने वाले एमएनएफ के दस्ते में वे शामिल थे.

एमएनएफ बागियों की भूमिका में बदलाव के सबसे सटीक प्रतीक हैं पूर्व बागी 44 वर्षीय तॉनलुइया. वे एमएनएफ के सेनाध्यक्ष थे. अब वे ललडेंगा सरकार में राहत और पुनर्वास-मंत्री हैं. उनका प्रमुख काम है अपने पुराने बागी साथियों की परेशानियों को दूर करना ताकि वे सामान्य जिंदगी जी सकें. उनके मुताबिक एमएनएफ के उनके पूर्व बागी साथियों को सामान्य जीवन जीने में ज्यादा मनोवैज्ञानिक परेशानियां इसलिए नहीं भुगतनी पड़ीं क्योंकि जब वे खुले में आए तो लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया.

एमएनएफ के डॉक्टर रह चुके 38 वर्षीय थंग्दाइलोवा कहते हैं, "हमने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल मिजो लोगों की खातिर लड़ते हुए कुर्बान कर दिए. लोग इस बात को महसूस करते हैं. हम लोगों ने अपनेआप को कभी बहिष्कृत नहीं महसूस किया क्योंकि हमें पूरी इज्जत मिली. लोग हमेशा हमारी मदद ही करते हैं." चीन में एक्युपंचर चिकित्सा का प्रशिक्षण ले चुके थंग्दाइलोवा सरकारी ठेकेदार बनना चाहते हैं.

ज्यादातर बागी धीरे-धीरे व्यवस्थित हो रहे हैं और सामान्य जीवन बिताने की तैयारियों में जुटे हैं. आठ वर्षों की अपनी बागी जिंदगी में तीन मुठभेड़ों में किसी तरह बच निकले 28 वर्षीय लांग्चाविया ने पिछले अगस्त में शादी कर ली. उन्हें यह एक विडंबना ही लगती है कि वे पुलिस का सिपाही बनने वाले हैं. लेकिन उन्हें यह नहीं लगता कि उनके बगावत के दिन बेकार चले गए. वे दृढ़ता से कहते हैं, "लड़ाई व्यर्थ नहीं गई. बगावत की वजह से ही केंद्र ने राज्य की ओर ध्यान दिया."

पहले के मुकाबले एकदम विपरीत भूमिका निभा रहे ललडेंगा कहते हैं कि उन्हें एक चुनौती भरा काम अंजाम देना है. संचार माध्यमों की कमी की वजह से पूरा राज्य अभी भी देश से पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है. उसे अभी राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना है. वे अनाज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. साथ ही वे राज्य के जंगलों की कटाई पर रोक और लघु उद्योगों की शुरुआत करना चाहते हैं. वे राजनीति के दांवपेंच भी सीख रहे हैं. एमएनएफ में असंतोष न भड़के इस डर से वे उन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

इस तरह 41 वर्षीय एफ. रोडियंग्लियाना ने भी अपनी जिंदगी के 20 साल बागी रहकर गुजारे हैं. अब सामान्य जिंदगी जीते हुए उन्हें लगता है कि बागी जीवन के वे दो दशक ही 'जिंदगी के बेहतरीन साल' थे. यों ही बेकार नहीं गया वह दौर. उन्होंने आइजोल में फलों के रस और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की अपनी दुकान खोलने का फैसला किया. अब वे हर महीने तकरीबन 5,000 रु. कमा रहे हैं और सामान्य जीवन की खुशियां बटोर रहे हैं.

हालात बदलने के साथ ही इसी तरह खुली जिंदगी में लौट आए बाकी लोग भी खुश हैं. 29 वर्षीय ललबियाका अब सरकारी ठेकेदार बन गए हैं. उनका धंधा फलने-फूलने लगा है. 14 साल जंगल में गुजारने के बाद उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया, खास तौर पर तब जबकि एमएनएफ सत्ता में आ गई.

लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस जंगल में जाने के इच्छुक हैं. 30 वर्षीय जहित्रग्थंग ऐसे ही बागी हैं. उन्हें जंगल का जीवन ही भाता है. जंगल के बुरे से बुरे हालात में जीना सीख चुका यह पूर्व बागी अब वन रक्षक बनना चाहता है.

इसमें शक नहीं कि एमएनएफ के इन पूर्व बागियों को सरकारी पुनर्वास कार्यक्रम का फायदा मिला है. यह कार्यक्रम अपनेआप में अनूठा था. शुरू में हरेक को 2,000 रु. दिए गए ताकि वे अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें. इसके बाद उन्हें 20-20 हजार रुपए की एक और मदद राशि दी गई ताकि वे घरेलू इस्तेमाल का सामान खरीद सकें. हरेक को घर बनाने के लिए आधा बीघा जमीन (तकरीबन 7,500 वर्ग फीट) और 40,000 रुपए का अनुदान देने की भी योजना बनाई गई. आवासीय अनुदान के अलावा हर तरह का अनुदान उन्हें दिया गया है. इस जून तक आवासीय अनुदान की आधी धनराशि यानी 20-20 हजार रुपए भी वितरित कर दी जाने की संभावना है. किसी के लिए भी यह किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं है. रोडियंग्लियाना जैसे लोगों ने सारे पैसे को धंधे में लगा दिया. पर कई ऐसे भी हैं जिन्होंने शराब व मौज-मस्ती में पैसा उड़ा दिया और अब पछता रहे हैं.

ऐसे ही लोग अब परेशानी पैदा कर रहे हैं. पिछले साल इन पूर्व बागियों के एक तबके ने तो बाकायदा रेमना इन चौक एसोसिएशन नामक एक संगठन तक बना लिया था. 200

सभी फोटो: प्रणात पंजियार

खाद्य पदार्थों की अपनी दुकान में रोडियंग्लियाना (दाएं): नई उम्मीदें

सामान्य घरेलू जीवन जीने में जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सदस्यता का दावा करने वाला यह संगठन नाराज था कि ललडेंगा सरकार उनसे अच्छा बरताव नहीं कर रही है. इन असंतुष्टों का दावा है कि उन्होंने सहायता में मिला सारा पैसा चुनाव प्रचार के लिए एमएनएफ को दे दिया था. एसोसिएशन बनते ही मुख्यमंत्री ने इसके महासचिव 32 वर्षीय सी. वनललरुआता को एमएनएफ से निकाल दिया. तॉनलुइया, इस बात से इनकार नहीं करते कि कुछ पूर्व बागियों ने चुनाव प्रचार के लिए पैसा दिया था.

असल में, पुनर्वास राशि को उड़ा देने के लिए ज्यादातर पूर्व बागी खुद ही जिम्मेदार हैं. उनमें से 40 से भी ज्यादा को टैक्सी का परमिट दिया गया पर उन्होंने इसे टैक्सीवालों को बेच दिया. आइजोल के रेमना शिविर में अस्थायी तौर पर ऐसे 35 परिवारों को बसाया गया. उनमें से कुछ का पुनर्वास होना अभी बाकी है.

बिजली महकमे के एक ठेकेदार और एसोसिएशन के प्रवक्ता पैट्रिक हउनर का कहना है कि राज्य सरकार ने सिर्फ एमएनएफ के आला कमांडरों को ही फिर से बसाने पर ज्यादा ध्यान दिया और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए या तो छोटे-मोटे काम-धंधे छोड़ दिए या उन्हें अपनी किस्मत के भरोसे. ललडेंगा इसे नहीं मानते. वे कहते हैं कि सरकार हर किसी के साथ न्याय करने को प्रयत्नशील है पर असंतोष इसलिए भड़का है क्योंकि केंद्र जानबूझकर पुनर्वास अनुदान देने में देरी कर रहा है. पिछले पखवाड़े केंद्र ने आवास अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी. लगता है कि अब ललडेंगा पर दबाव कम हो जाएगा.

पुनर्वास मंत्री तॉनलुइया अपने दफ्तर में: नई जिम्मेदारियां

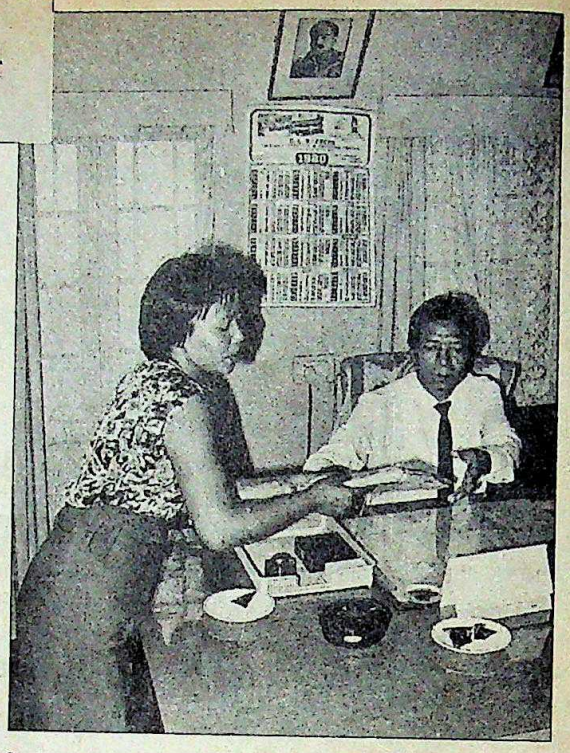

"अब हम मिजोरम को एक आदर्श राज्य बनाने में जुटे हैं. हमारा सारा ध्यान रचना में लगा है, विनाश में नहीं"

पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें असल में पुनर्वास की कोई भी सुविधा नहीं मिली फिर भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया. ऐसी ही एक मिसाल हैं 47 वर्षीया तिनसंगी. वे छह साल तक भूमिगत रहीं. उस दौरान एमएनएफ के शिविरों में नर्स का काम किया. अब उन्होंने आइजोल में दवाइयों की एक दुकान खोल ली है जिससे वे 50,000 रुपए का सालाना कारोबार कर रही हैं. जंगल की जिंदगी जीते हुए उन्होंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी.

बहरहाल, कुछ असंतुष्ट तत्वों को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर पूर्व बागियों की जिंदगी को एक नया मकसद मिला है. जो बागी फिर से अपने बिछुड़े परिवारों से आ मिले हैं उनको देखकर यह तथ्य और भी स्पष्ट होता है. कई तो ऐसे थे जो अपने बच्चों को बड़े होते देखने की खुशी से अछूते थे. आज वे इसका आनंद उठा रहे हैं. इन लोगों में तॉनलुइया भी हैं. लगातार लुकते-छिपते जीवन बिताते हुए 20 साल में उन्होंने अपनी पत्नी हर्मिगी को सिर्फ तीन बार देखा था. उनके भूमिगत हो जाने के कुछ दिनों बाद उनके बेटे ने जन्म लिया था और अब वह कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र है. पर तॉनलुइया कहते हैं कि लंबे समय तक अलग रहने की मजबूरी के बाद अब पारिवारिक बंधन ज्यादा मजबूत हो गए हैं. वे बताते हैं, "हर शाम दफ्तर से मुझे घर लौटते देखकर मेरी पत्नी खुशी से झूम उठती है."

रोडियंग्लियाना अब अपने तीन बच्चों के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकते. वे हर रोज उनके साथ उनकी दुकान में जाते हैं और आसपास खेलते हैं. वे कहते हैं, "सामान्य घरेलू जिंदगी जीने में भी असीम आनंद है." ज्यादातर मिजो बागी इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं.

एमएनएफ में नर्स रह चुकी तिनसंगी अपनी दुकान में: समृद्धि

"जंगल के जीवन में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी खुशहाल हो सकूंगी"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिन डूबा तिन पाइंया

पोलियोग्रस्त टांगों वाला कोई बच्चा तालाब में डुबकी लगाए और मोती निकाल लाए तो है न अविश्वसनीय बात! लेकिन यह करिश्मा कलकत्ता के एक स्कूली छात्र पार्थ दास ने कर दिखाया है. 28 मई को जब उसने विद्यासागर सरोवर में गोता लगाया तो उसके हाथ कुछ मोती आ लगे. और ज्योंही यह खबर फैली, मोती के खजाने की खोज में गोते लगाने वालों का तांता लग गया.

फोटो: गैबाल दास

मोती के साथ पार्थ: किस्मत आजमाने वालों का तांता

कई लोगों ने तो राज्य सरकार द्वारा 'उन्नयन संघ' को मछली पालने के लिए पट्टे पर दिए इस सरोवर को खरीदने की भी पेशकश की. बताया जाता है कि अब तक इस सरोवर से लगभग सौ मोती निकाले जा चुके हैं. वहां रहने वाले एक बुजुर्ग अनिरुद्ध डे बताते हैं, "इस तालाब में निश्चित रूप से 30,000 से ज्यादा सीप हैं, जिनमें से 5,000 से ज्यादा सीपें विकसित हैं. इनमें आधे से ज्यादा में जरूर ही मोती मिल सकते हैं."

जब भीड़ काबू के बाहर हो गई तो संघ के अध्यक्ष एम.के. रुद्र ने सरकार से तालाब को अपने कब्जे में लेने और वहां पुलिस का पहरा बैठाने का सुझाव दिया. 8 जून को वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. जब भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) और भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग की आरंभिक रिपोर्ट मिली कि ये मोती सच्चे हैं तो वहां के लोग खुशी से झूम उठे. जीएसआई के शैल विज्ञान विभाग के निदेशक के.के. बसु बताते हैं, "समस्या यह है कि यह तय नहीं हो पा रहा कि ये मोती प्राकृतिक हैं या कृत्रिम प्रक्रिया से तैयार हुए हैं." मोती चाहे जिस विधि से बने हों, वहां के लोग अपने सरोवरों में सीप पालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

टकराव का कानूनी रंग

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण और उनके विरोधियों के बीच चल रही लड़ाई ने अब कानूनी रंग पकड़ लिया है. पिछले पखवाड़े बंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने चव्हाण, उनकी पत्नी कुसुमताई, बेटे अशोक, राज्य सरकार और नांदेड़ की नगरपालिका के नाम एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया.

यह नोटिस प्रगति महिला मंडल को जमीन के आंबटन और सई सेवा ट्रस्ट को एक लाख रु. का अनुदान देने के सिलसिले में भेजा गया. चव्हाण की पत्नी और पुत्र इन संस्थाओं से जुड़े बताए जाते हैं. याचिका दायर करने वाले पत्रकार अनिल कोहली ने आरोप लगाया है कि मंडल को दी गई जमीन नांदेड़ के मास्टर प्लान के अनुसार एक स्कूल के लिए आरक्षित थी. तब मुख्यमंत्री ने इन आरोपों का खंडन किया था कि उनके बेटे ने निजी लाभ के लिए उनके प्रभाव का इस्तेमाल किया है. खैर, चव्हाण को अपने को पाक-साफ साबित करने का एक मौका मिल गया है.

तमिलनाडु में गड़बड़झाला

तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों बेहद उलझ गई दिखती है. पिछले पखवाड़े केंद्रीय उर्वरक राज्यमंत्री आर. प्रभु मदुरै में थे. वहां उन्होंने राज्य विधानसभा चुनावों में देरी के लिए अफसोस जाहिर किया. लेकिन प्रदेश इंका अध्यक्ष जी.के. मूपनार चाहते हैं कि चुनाव फिलहाल स्थगित ही रहें तो ठीक ताकि राज्य में पार्टी की छवि सुधारने का और समय मिल जाए. इसके अलावा एक और मुद्दे पर इंकाई दो धड़ों में बंट गए हैं. राज्य के प्रायः सभी पार्टी नेता विधानसभा चुनाव जहां अपने ही बूते पर लड़ना चाहते हैं, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह समेत कई केंद्रीय नेता अन्ना द्रमुक के जयललिता गुट के साथ गठबंधन करना चाहते हैं.

जयललिता गुट में भी ऐसा ही मतभेद उभरने लगा है. एस. रामचंद्रन और एस. थिरुनावुकरसु जहां इंका की भावनाओं की कद्र करने के इच्छुक हैं, वहीं जयललिता और वी.आर. नेडुनचेड़ियन इस गठबंधन पर हावी होना चाहते हैं. जानकी गुट के पूर्व मंत्री पोन्नियन इंका के साथ समझौते के इच्छुक हैं. लेकिन गुट के आर.एम. वीरप्पन और के. कैलमुथु जैसे लोग विभाजन के कगार पर खड़ी द्रमुक के साथ गठजोड़ करना चाहते हैं. अब इस गड़बड़झाले में यह तय कर पाना कठिन हो रहा है कि कौन किसका समर्थन कर रहा है, किसका नहीं.

सपना का दुःस्वप्न

नन्हीं सपना के माता-पिता को शायद उसकी किलकारियां सुनने की इच्छा नहीं थी. इस दुनिया में आए उसे एक ही दिन बीता था कि उसके माता-पिता उसे कर्नाटक में मनिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छोड़ गए. तब से यह अस्पताल ही उसका घर है. बच्ची का कसूर यह है कि वह विकृत पैदा हुई थी. उडुपि जिले में जन्मी इस बच्ची को अस्पताल के अधिकारियों को सौंपते हुए उसके माता-पिता ने कहा था कि वे एक विकृत शिशु के भरण-पोषण का बोझ नहीं उठा पाएंगे. यह बच्ची 'फोकोमीलिया' से ग्रस्त है. इस बीमारी में गर्भस्थ शिशु के हाथ-पैर

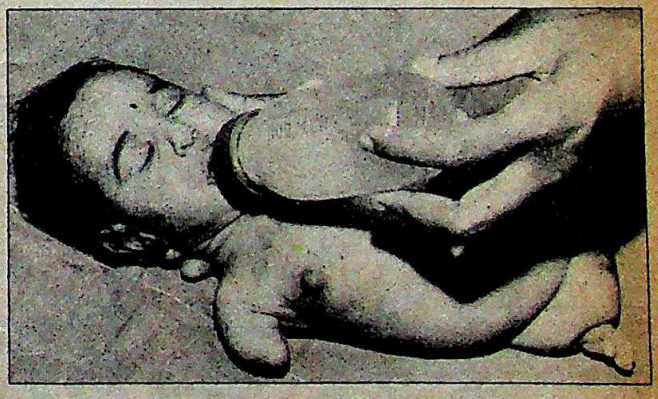

सपना: अस्पताल ही घर है

के स्थान पर उंगलियों के समान मांस के लोथड़े उभर आते हैं.

बहरहाल, सपना की देखभाल करने वालों की कमी नहीं है. अस्पताल का पूरा स्टॉफ बड़े जतन से उसकी देखभाल करता है. उसके शुभचिंतकों में दूध वाला भी शामिल है, जो उसके लिए मुफ्त दूध दे जाता है और बंगलूर का अनाथ आश्रम 'आश्रय' भी जिसने उसे पालने का जिम्मा लेने की पेशकश की है. लेकिन अस्पताल के डॉ. एच.एस. मोहन कहते हैं, "ऐसे बच्चों में अंगों के प्रत्यारोपण की संभावना बहुत कम होती है, और इसमें खर्च भी बहुत आएगा."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में प्रतियोगिता परीक्षा अ

सफलता, उन्नति एवं लोकप्रियता के कीर्तिमान

पत्रिका एक-उद्देश्य अनेक

प्रतियोगि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...अहेतु हिन्दी की प्रथम पत्रिका

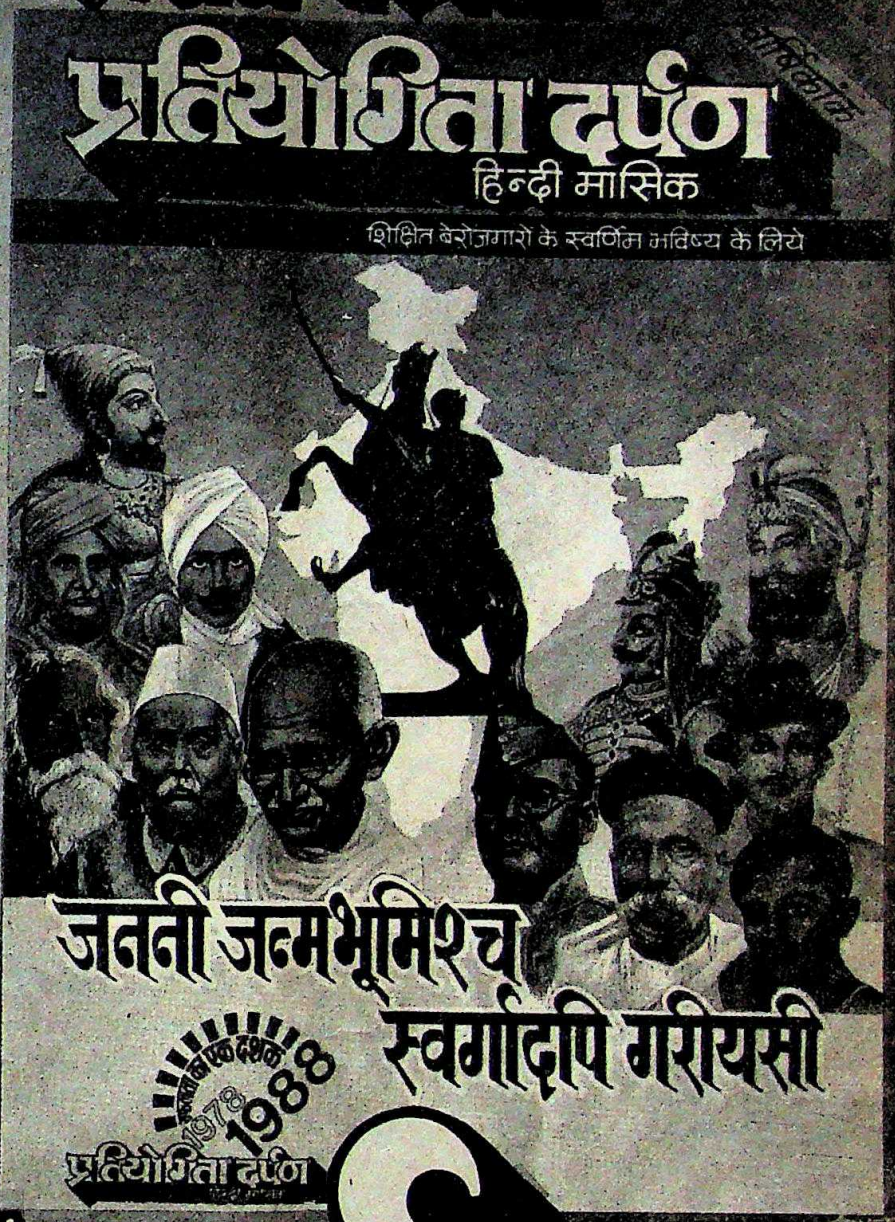

अगस्त अंक के विशेष आकर्षण

- गत बारह माह के अंकों का सार संक्षेप
- वर्ष भर की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का संक्षिप्त विवरण
- वर्ष भर के चर्चित व्यक्ति व स्थान, पुरस्कार, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ आदि
- विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं से सम्बद्ध हल प्रश्न-पत्र
- महत्वपूर्ण सम-सामयिक, विज्ञान, कृषि, आर्थिक कला व संस्कृति एवं भौगोलिक निबन्ध आदि
- विश्व एवं भारत सम्बन्धी विविध तथ्य
- महान व्यक्तित्व-राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त
- विविध रोजगार विषयक नवीन पाठ्यक्रमों पर महत्वपूर्ण सामग्री
- रोजगार समाचार
- साथ में सभी स्थाई स्तम्भ व अन्य महत्वपूर्ण सामग्री

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराइए

मूल्य 13/- रुपए

...ता दर्पण

हिन्दी मासिक

सही मार्गदर्शन-प्रेरक ...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इरादा बदला

हिंदुस्तान लीवर ने बंबई की एक अनजान-सी कंपनी नार्डेन इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इत्र और सुवास बनाने वाली इस कंपनी को अपने में शामिल करने के बाद लीवर उसमें दिलचस्पी लेने लगी और उसके मुख्य कार्याधिकारी के शेयर हासिल कर लिए. बाद में मुख्य कार्याधिकारी ने लीवर के व्यक्ति के लिए पद छोड़ दिया.

अब लीवर और एक कदम आगे बढ़ गई है. उसने कंपनी में एम.आर. छाबरिया की 12 फीसदी शेयर होल्डिंग खरीद ली है. छाबरिया ने इन्हें गॉर्डन बुड्रॉफ के जरिये लिया था. उन्होंने शुरू में तो अपने शेयर खरीदने की लीवर की पेशकश ठुकरा दी थी और शेयरों को गॉर्डन बुड्रॉफ से शॉ वैलेस को हस्तांतरित करने की कोशिश की थी लेकिन अब उनका इरादा बदल गया है और उन्होंने लीवर को शेयर बेचने का फैसला कर लिया है.

अखाड़ा और उठापटक

उत्तर प्रदेश में बड़ी परियोजनाएं हथियाने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों में उठापटक चल रही है. आदित्य बिड़ला ने तो इंडो-गल्फ उर्वरक परियोजना हथिया ली है. लेकिन सलेमपुर ऐरोमैटिक्स परियोजना अभी तक किसी के हाथ में नहीं गई है. इस परियोजना के लिए रिलायंस, बिड़ला और सिंघानिया के बीच खूब उठापटक हुई थी.

अब लिनीयर एल्काइल बेंजीन के उत्पादन वाली एक बड़ी योजना के लिए जद्दोजहद चल रही है. इस लड़ाई में भी सिंघानिया समूह का स्टॉ प्रोडक्ट्स, आदित्य बिड़ला का ग्रेसिर्ग उद्योग समूह और श्याम भरतिया का वाम ऑर्गनिक्स शामिल है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह ने वाम के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है लेकिन केंद्र से मंजूरी मिलना अभी भी संदिग्ध है.

बड़ों को भी रियायतें

लगता है, सरकार उद्योग नीति को और उदार बनाने की नई रियायतों की घोषणा करने जा रही है. इसके पहले पिछड़े इलाकों की तरक्की के लिए रियायतों की घोषणा की गई थी. पर एमआरटीपी और फेरा के तहत आने वाली कंपनियों को इससे वंचित रखा गया था. अब इन दोनों श्रेणियों की कंपनियों के लिए भी रियायतों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं.

नई रियायतों के साथ-साथ सरकार पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के नए कदम के रूप में लाभांश आय पर से कर खत्म करने के प्रस्ताव पर भी गौर कर रही है. वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी को लगता है कि इस कदम से सरकारी खजाने को बहुत थोड़ा (लगभग 86 करोड़ रु.) नुकसान उठाना पड़ेगा. लेकिन इस कदम के विरोध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सामने आ गया है.

पूंजी के लिए

पांच सौ करोड़ रु. के पूंजी निर्गम के लिए रिलायंस उद्योग अब पूंजी निवेश करने वालों के पास दूसरे तरीके से जाएगा. वित्त मंत्रालय में पूंजी निर्गमों के नियंत्रक की आपत्ति थी कि रिलायंस की शेयर जारी करने की योजना बहुत ही जटिल है और इससे पूंजी निवेश करने वाले उलझन में पड़ेंगे. लिहाजा रिलायंस ने संचयी परिवर्तनीय वरीयता शेयर जारी करने के प्रस्ताव को तिलांजलि देने का फैसला किया है. कंपनी अब समूचा पूंजी निर्गम सामान्य परिवर्तनीय ऋणपत्रों के रूप में करेगी. इनके अगले दो महीने में बाजार में आ जाने की संभावना है.

मुनाफे का मामला

कंपनियों के मुनाफे में सुधार के लक्षण दिखने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़े कुछ दूसरी ही कहानी कहते हैं. इनसे पता चलता है कि निगमित क्षेत्र उतने फायदे में नहीं चल रहा जितनी कि उम्मीदें की जाती हैं. उनका लाभ घट रहा है. इन आंकड़ों के मुताबिक 113 कंपनियों को इस साल मई में कर देने के बाद कुल 64 करोड़ रु. का लाभ हुआ जबकि पिछले साल इसी अवधि में उन्हें 81 करोड़ रु. का लाभ हुआ था. जून 1987 से मई 1988 तक की अवधि में 663 कंपनियों को कर देने के बाद कुल 1,014 करोड़ रु. का लाभ हुआ था. यानी मुनाफे में 21 फीसदी की भारी कमी आई. कंपनियों की बिक्री में 11 फीसदी की बढोतरी और ब्याज तथा कर देने से पहले मुनाफे की रकम 3 फीसदी बढ़ने के बावजूद ऐसा हुआ है.

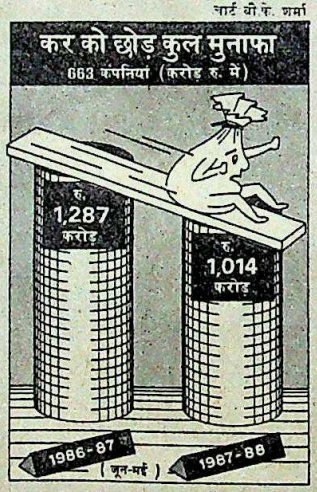

खाड़ी में दूसरी लड़ाई

छाबरिया और हिंदुजा के बीच की प्रतिस्पर्धा अब खाड़ी देशों में भी पहुंच गई हैं. छाबरिया बंधु अशोक लेलैंड के लिए चली लड़ाई में हिंदुजा भाइयों से पहले ही मात खा चुके हैं. पिछले महीने वे उनसे दूसरे दौर में भी परास्त हो गए जब वित्त और वाणिज्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने निर्यात के बढ़ावे के लिए आप्रवासी भारतीयों की 20 सदस्यीय समिति की घोषणा की.

नई दिल्ली में अपना प्रभाव जमाने के इच्छुक छाबरिया ने समिति में शामिल होने के लिए बड़े हाथ-पांव मारे. लेकिन अंतिम क्षण में हिंदुजा भाइयों के एक संबंधी दुबई के रमेश मेंडा ने उनका पत्ता कटवा दिया और अपना नाम दर्ज करवा लिया.

मेंडा को समिति में रखने से ओवरसीज इंडियन इकॉनामिक फोरम खीज गया है. संयुक्त अरब अमीरात में आप्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन निर्यात पर आप्रवासी भारतीयों का एक बड़ा सेमिनार आयोजित करने जा रहा है लेकिन वह इस सम्मेलन से मेंडा को दूर ही रखने का इच्छुक है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो देश में लोकप्रिय हो, उसे नैशनल कहते होंगे– आप चुनिये वो – जो इन्टरनैशनल है!

अकाइ VS-23

केवल अकाइ में इतने सारे गुण AKAI

क्विक स्टार्ट (प्ले और रेकार्ड)
बस बटन दबा और तस्वीर तुरन्त उभरी केवल डेढ़ सेकन्ड में! अन्य वी. सी.आर. पर इसमें लगते हैं ८ सेकन्ड।

क्विक इन्डेक्स सर्च
जो कार्यक्रम आप देखना चाहें, यह उसी को शुरू से लगाये। ढूंढते रहने की ज़रूरत नहीं।

क्विक इन्ट्रो स्कैन
तलाश के तुक्के लगाना बन्द। इन्डेक्स सिग्नल वाले कार्यक्रम के प्रथम भाग ८ सेकन्ड तक दिखाकर, ये चुनाव में मदद करे।

इन्टर एक्टिव मॉनिटर सिस्टम
किस काम के लिये कौनसा बटन दबाना, यह स्क्रीन पर बताये।

सुपर क्लियर स्लो मोशन
टेप चलाने की गति को कम करने से, यह मनचाहा दृश्य स्लो मोशन में भी साफ़ दिखाये।

डबल स्पीड प्लेबैक
टेप का मनचाहा हिस्सा ढूंढने के लिये दुगनी स्पीड का प्रबन्ध।

सुपर स्टिल
चलचित्र को स्थिर कर दीजिये। या एक एक फ्रेम आगे बढ़ाइये।

हाई क्वालिटी सिस्टम
एच. क्यू. सिस्टम द्वारा चित्र बहुत साफ़ दिखाये, हर बारीकी निखारे। "CCD नॉइज़ कैन्सलर" ध्वनि से शोर मिटाये।

इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड लॉक सिस्टम
बच्चों को उन कार्यक्रमों से बचाये रखे, जो उनके देखने योग्य नहीं।

10-की वायरलेस रिमोट
अनुपम १० बटनों वाला रिमोट कन्ट्रोल– टाइमर प्रोग्रैमिंग से लेकर ट्रैकिंग तक हर काम करे।

4 प्रोग्रॉम 1 महीना टाइमर
आपकी पसन्द के टी.वी. कार्यक्रम अपने आप नियुक्त समय पर रेकॉर्ड करे।

युनीक टेप व्यू सिस्टम
चलता हुआ टेप दिखाई देने का प्रबन्ध, जिससे आप ठीक से जान सकें कि कितना टेप बचा है।

मेमरी बैक-अप
बैटरी बैक-अप सिस्टम, पावर फ़ेल हो जाने पर भी एक घन्टे तक मेमरी सुरक्षित रखे

अन्य गुण
62 टी.वी. प्रीसेट स्टेशन, क्विक टाइमर, ऑटो पावर ऑन, ऑटो प्ले, ऑटो रिजेक्ट, ऑटो रिवाइन्ड, पावर ऑफ़ इजेक्ट, ऑटो काउन्टर डिस्प्ले, ऑटो डिमर क्लॉक।

मुफ़्त वारन्टी
अकाइ एक्विपमेन्ट यू.ए.ई. में ख़रीदने पर साथमें यह वारन्टी कार्ड मुफ़्त मिलेगा। यह कार्ड इस बात की गारन्टी है कि भारत, इजिप्त, जॉर्डन, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, सिरिया और थाइलैन्ड में बढ़िया सर्विस भी मिलेगी, और पुर्ज़े भी मुफ़्त बदले जासकेंगे।

GENERAL ENTERPRISES CO.
P.O. Box 363, Dubai, U.A.E., Tel: 224131, 236575,
Tlx: 45528 GECO EM, Fax: 281703

GECO

जीको के वादे से सशक्त।
क्वालिटी का वादा–
सर्विस का वादा।

INCA/AK/249

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंदुजा बंधु

जड़ें जमाने की जद्दोजहद

कारोबार के विस्तार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं

एक नई उथलपुथल की तैयारी है. अब तक गुमनाम रहे हिंदुजा बंधु औद्योगिक मंच पर बिजली की तरह कौंधने वाले हैं. अपनी कलंकित छवि को धो देने के मजबूत इरादे के साथ हिंदुजा बंधु (श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक) आगे बढ़ रहे हैं. उनके हर कदम से यही लग रहा है कि जैसे उन्होंने भारतीय उद्योग जगत में अपनी जड़ें गहरी जमाने की लंबी-चौड़ी योजना बना रखी है.

हिंदुजा घराने के आला सलाहकारों के मुताबिक वे जनता और व्यावसायिक जगत के बीच अपनी साख जमाने का दृढ़ संकल्प कर चुके हैं. और इस उद्देश्य की प्राप्ति का तरीका? इस देश में अपना भारी-भरकम उत्पादन तंत्र कायम करना, कुछ कंपनियों को हथियाना और लाभकारी निवेश करना. इनके अब तक के नतीजे? शानदार!

पिछले साल अक्तूबर में हिंदुजा घराने ने मद्रास की ट्रक बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड में 40 फीसदी और इसकी सहयोगी कंपनी एन्नोर फाउंड्री में 60 फीसदी साझेदारी हासिल कर ली. साथ ही पिछले साल इस घराने ने हैदराबाद की आईडीएल केमिकल्स के निदेशक मंडल में अपना एक आदमी बैठा दिया. 50 करोड़ की आईडीएल की बंगलूर की दवा कंपनी आस्ट्रा-आईडीएल में 25 फीसदी साझेदारी है.

दो साल पहले हिंदुजा बंधुओं ने आईडीएल पर अपना हाथ आजमाया था और स्वीडन की नाइट्रो नोबेल के सहयोग से अमेरिका की डॉ. केमिकल्स में 39.9 फीसदी की हिस्सेदारी हासिल कर ली थी. पिछले कुछ महीनों में हिंदुजा बंधुओं ने कई भारतीय कंपनियों पर काबिज होने की कोशिश की और लाभकारी परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे. हिंदुजा बंधु अब कुछ दूसरे क्षेत्रों में कम-से-कम 350 करोड़ रुपए लगाने की सोच रहे हैं. इस अभियान के लिए उन्होंने बंबई में बाकायदा एक विशेष परियोजना सेल बनाई है.

जरूरी इजाजतें हासिल करने के लिए अर्जियां दाखिल कर दी गई हैं.

► एक अर्जी बंबई से 'इंटरनेशनल हेरॉल्ड ट्रिब्यून' का संस्करण निकालने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय में दी गई है. यह अखबार उपग्रह संचार के जरिये पेरिस मुख्यालय की मदद से छपेगा और इसे भारत तथा खाड़ी के देशों में बेचा जाएगा. इसकी शुरुआत 25,000 से 30,000 प्रतियां छापकर की जाएगी.

► दूसरी अर्जी उन्होंने फ्रांस की कंपनी सीआईटी अल्काटेल (जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय टेलीफोन उद्योग को तकनीक सप्लाई कर चुकी है) के सहयोग से 10 करोड़ डॉलर की लागत वाली टेलीफोन स्विचिंग उपकरण उत्पादन परियोजना के लिए है.

► एक अर्जी अल्फा-आलेफिस बनाने की 100 करोड़ रुपए की पेट्रोकेमिकल्स परियोजना की मंजूरी के लिए रसायन व पेट्रोलियम विभाग में पड़ी है.

यह घराना गुजरात राज्य औद्योगिक विकास निगम (जीएसआईडीसी) के साथ मिलकर अल्यूमिनियम की पन्नी बनाने का कारखाना लगाने पर भी विचार कर रहा है. 1982 से ही जीएसआईडीसी के पास इसका लाइसेंस है. अब जबसे हिंदुजा ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की है तबसे परियोजना के लिए जरूरी तकनीक और पूंजी निवेश का आकलन फिर से शुरू हो गया है.

कंपनी अधिग्रहण और लाभकारी निवेशों के जरिये भारतीय उद्योग जगत में अपनी जड़ें गहरी जमाकर हिंदुजा बंधु अपनी छवि बनाना और साख जमाना चाहते हैं

इस बीच हिंदुजा बंधु कंपनियों की अधिग्रहण की अपनी कोशिशों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं. उनकी पहली कोशिश मद्रास की कंपनी वेस्ट ऐंड क्रांप्टन में घुसने की है. 121 करोड़ रुपए की यह कंपनी अशोक लेलैंड को ढले हुए सांचे बेचती है और इसके अलावा

कार्टून: अजीत नैनन

बिजली के उपकरणों का धंधा भी करती है. इसी तरह केरल की हैरीसंस मलयालम प्लांटेशन (कारोबार: 62 करोड़ रु.) के अधिग्रहण की भी वे कोशिश चला रहे हैं. इसके 40 फीसदी शेयर विदेश में हैरीसंस ग्रीनफील्ड के पास हैं. वैसे एमआरएफ टायर कंपनी भी मलयालम प्लांटेशन के लिए भागदौड़ कर रही थी. इसके विदेशी शेयरों को खरीदने के लिए एमआरएफ 15 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा चाहती थी. इसके लिए उसकी अर्जी पर अभी रिजर्व बैंक विचार कर रहा था कि हिंदुजा बंधुओं ने हैरीसंस ग्रीनफील्ड को ही खरीद लिया.

यह सब भारत में हिंदुजा साम्राज्य के विस्तार का एक छोटा-सा किस्सा है. अधिग्रहण, निवेश और नए विचारों के साथ उद्योग जगत पर दस्तक दे रहे ये चारों भाई अब मामूली व्यापारी बताकर टरकाए नहीं जा सकते. पहले के आप्रवासी 'हमलावरों' के विपरीत हिंदुजा घराने ने यह हमला मखमल के दस्ताने पहनकर बोला है. घराने के अध्यक्ष श्रीचंद हिंदुजा ने 'इंडिया टुडे' को बताया, "किसी कंपनी के मौजूदा प्रबंधन को कमजोर करने या शेयर बाजार पर अचानक ही धावा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बोलने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं. न ही हम घरानों की मिल्कियत वाले धंधों में दखल देना चाहते हैं." पर यह तय है कि मौका आने पर वे लड़ाई लड़ने से पीछे रहने वाले भी नहीं. अशोक लेलैंड पर काबिज होने के लिए जिस तरह से राहुल बजाज को किनारे किया गया उससे तो यही जाहिर होता है.

बाकी सारे आप्रवासी हमलावरों की तरह ही उन्होंने भारतीय कंपनियों के शेयरों के समुद्र में गहरे पैठ कर खलबली मचाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है. मोटर से लेकर रबर तक और रसायनों से लेकर दवा उद्योग तक की किसी भी कंपनी के अधिग्रहण या प्रस्तावित अधिग्रहण में भले ही कोई समानता न दिखे पर यह संयोग हो या सोच, एक समानता यह दिखती है कि हिंदुजा बंधु सिर्फ दक्षिण भारत में ही घुसपैठ कर रहे हैं.

लेकिन इसी समानता की वजह से उनकी दिलचस्पी वेस्ट ऐंड क्रांप्टन में जागी. खबर थी कि इस पुरानी फाउंड्री को हथियाया जा सकता है. इसके ढलवां सामान की प्रमुख ग्राहक अशोक लेलैंड है. हिंदुजा बंदुओं ने पहले फाउंड्री और फिर पूरी कंपनी को

वे कुछ नए क्षेत्रों में कम-से-कम 350 करोड़ रु. लगाने की सोच रहे हैं. इस अभियान के लिए उन्होंने बंबई में बाकायदा एक विशेष परियोजना सेल बनाई है

खरीदने की बात सोची थी. वे उसके शेयर की मूल कीमत का चार गुना देने को तैयार थे, पर वित्तीय संस्थान और ज्यादातर शेयर-धारक अपने शेयर देने को तैयार नहीं हैं.

पर हिंदुजा के लिए पिछला दरवाजा खुल सकता है. वेस्ट ऐंड क्रांप्टन की मुख्य समस्या है चल पूंजी की कमी और इस मामले में वित्तीय संस्थानों के मुकाबले हिंदुजा की स्थिति ज्यादा पुख्ता है.

हिंदुजा बंधु 1,755 करोड़ रुपए के बोफर्स सौदे और 540 करोड़ रुपए के एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी के ठेके को लेकर इस कदर बदनाम हो चुके हैं कि उनके लिए अब अहम समस्या उनकी छवि की है. '70 के दशक में जब पहली बार भारत में उनकी मौजूदगी दर्ज की गई तब से वे बिचौलियों और पैसा लगाने वालों की अंधेरी-धुंधलकी दुनिया में ही थे, उद्योगों का प्रबंधन उनके लिए नया तजुर्बा ही है.

पर अब ये लोग कामयाब अगुआ बने हुए हैं. जबकि तीन भाई लंबा-चौड़ा विश्वव्यापी साम्राज्य (जिसका कुल आकार अभी भी एक रहस्य है) संभालते हैं, छोटा भाई अशोक बंबई में फिल्मों में पैसा लगाने और समाज-सेवी कामों को देखता है.

अशोक लेलैंड का मामला उनकी अग्निपरीक्षा थी. भारी वाहन बनाने वाली इस कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य कहते हैं, "बोर्ड में जो फेरबदल किए गए हैं वे तो होने ही थे." पिछले नियंत्रकों (रोवर) का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक हटा दिए गए और उनकी जगह हिंदुजा समूह व इवेको के व्यावसायिक प्रबंधक बिठा दिए गए. इटली की ट्रक निर्माता इवेको इस अधिग्रहण में हिंदुजा के साथ थी. साथ ही हिंदुजा समूह के दो मनोनीत सदस्य रिटायर होने वाले दो सदस्यों की जगह बोर्ड में शामिल हुए.

कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज में हिंदुजा बंधुओं ने कोई दखल नहीं दिया. बोर्ड के एक सदस्य कहते हैं, "कंपनी को व्यावसायिक लोग ही चला रहे हैं." बोर्ड के पुराने फैसले भी नहीं बदले गए. मसलन अशोक लेलैंड ने ट्रक इंजन बनाने के लिए जापान के हीनो से समझौता किया था. यह फैसला अभी बरकरार है. हिंदुजा समूह ने अपने व्यापार संपर्कों के जरिये निर्यात को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव रखा है, खास तौर पर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में.

इस बीच हिंदुजा के एक सलाहकार का कहना है, "वे अपने परियोजना आकलन दल को मजबूत बना रहे हैं. मैं नहीं समझता कि सही परियोजना के लिए पैसे की कमी कोई बाधा बनेगी." यानी अभी औद्योगिक अभियानों की कई बाजियां खेली जाएंगी और एक संदेहास्पद व्यापार समूह उत्पादन के क्षेत्र में घुसकर ही मानेगा. हिंदुजा बंधु जितना लंबा-चौड़ा जाल रच रहे हैं उससे कोई भी यह अंदाज लगा सकता है. यह साफ है कि वे कोई भी गलत कदम न उठाकर हर मुमकिन बेहतर काम की कोशिश कर रहे हैं. अगर वे गलत कदम उठाते हैं तो साख बहाली की उनकी कोशिशें नाकाम ही रहेंगी.

—आनंद पी. रमन, ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

अनिश्चितता के बाद नया जोश, नई तेजी

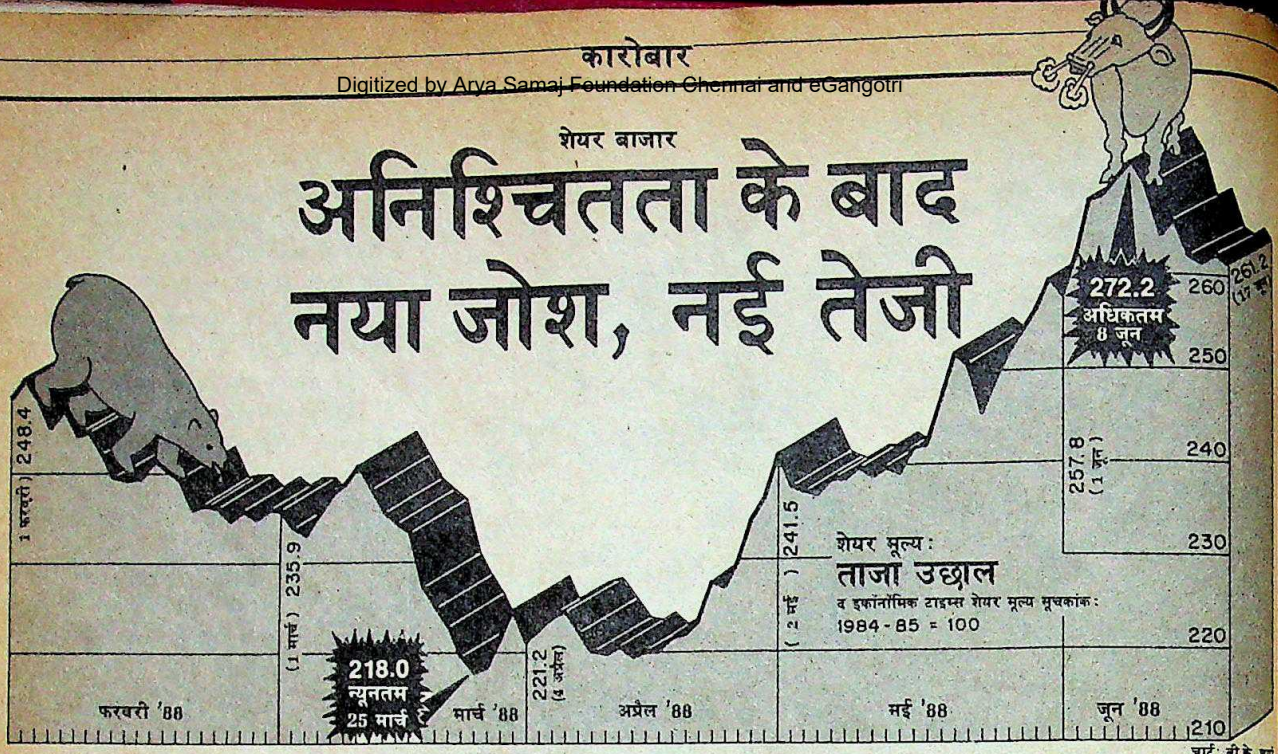

चार्ट: बी.के. झा

शेयर बाजार की छटा निराली है. यहां की हस्तियां अपनेआप में अजूबा हैं. वे कब चोला बदल लें, कहा नहीं जा सकता. अब तक हावी रहे मंदड़िये पिछले पखवाड़े मौके की ताक में बैठे दिखे, वे खामोश बैठ जाने के लिए तैयार नहीं थे. उधर अरसे बाद तेजड़ियों की निष्क्रियता टूटी. एकाएक उनके हरकत में आने से बाजार का रुख ही बदल गया. नया जोश, नई तेजी दिखाई देने लगी. लगा, शेयर बाजारों के भाग्य खुल गए.

लेकिन ऐन उस मौके पर जब निवेशकों में भरोसा बढ़ रहा था और प्रत्येक शेयर बाजार का सूचकांक बुलंदी की ओर था, हल्की-सी मंदी ने बाजार को आ घेरा. इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले आई तेजी अचानक हुई थी और तेजड़िये सक्रिय हो उठे थे. दूसरी वजह यह थी कि चुनाव के बाद अनिश्चितता का आलम छा जाने से सरकार में फेरबदल की चर्चा होने लगी थी.

लेकिन कुल मिलाकर शेयर बाजारों में नई आशा हावी रही, भले ही देश भर में मानसून के छींटों ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की उम्मीद पैदा कर दी थी. मसलन बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का संवदेनशील सूचकांक 29 मार्च को 398.4 पर था और दो ही महीनों में यह 230 अंक बढ़ गया. यह बढ़ोतरी 60 फीसदी से भी ज्यादा थी. 628 पर पहुंचा यह सूचकांक फरवरी 1986 की रिकार्ड तेजी से 36 अंक ही पीछे था, पर हल्की-सी मंदी ने इसे लाकर 577.24 पर पहुंचा दिया.

बाजार में तेजी का अगुआ रहा है रिलायंस उद्योग. उसके 10 रु. के शेयर का दाम तीन महीने पहले तक 70.50 रु. था. पिछले पखवाड़े यह एकाएक 217.50 रु. पर पहुंच गया, हालांकि बाद में यह घटकर 146 रु. पर आ गया. दूसरी दिग्गज कंपनियों के शेयर भी आसमान छूने लगे. टेल्को के, जिसने भारी मुनाफे के बाद अपने लाभांश दुगने से ज्यादा करके 23 फीसदी पर पहुंचा दिए हैं, शेयर मूल्य 437.50 रु. से बढ़कर 627.50 रु. हो गए जबकि एसोसिएटेड सीमेंट के 135 से छलांग लगाकर 205 रु. और ओरके के 18.25 से 43.50 रु. पर पहुंच गए. इस तरह महीनों तक कड़की के दौर से गुजरने के बाद अचानक ही एक मौका निवेशक के हाथ आ गया.

1986 की भारी मंदी में जिन निवेशकों के कपड़े तक बिक गए थे, वे पिछले पखवाड़े शेयर मूल्यों में अस्थायी गिरावट के बावजूद एक बार फिर दांव आजमाने लगे और जो

राम के. पिपरैया
प्रबंध निदेशक, अरिधि इन्वेस्टमेंट

"मुझे उम्मीद है कि शेयरों की कीमतें अगले बजट तक बढ़ती ही रहेंगी. हां, यह जरूर हो सकता है कि बीच-बीच में उतार-चढ़ाव के बहुत सारे मौके आएं"

एम.जे. फेरवानी
अध्यक्ष, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

"शेयर बाजार में तेजी बरकरार न रहे इसकी कोई भी वजह नहीं दिखती. बहरहाल, इतना तो निश्चित है कि सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कंपनियां महीनों से खरीदार न मिलने के डर से नए शेयर और डिबेंचर नहीं जारी कर रही थीं, वे भी निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए बेताब हो उठीं. बीएसई के हाल ही में चुने गए अध्यक्ष जी.बी. देसाई कहते हैं, "बाजार की तेजी के बारे में अब मैं आश्वस्त हूं. दीवाली से पहले ही यह नई बुलंदियों को छू लेंगे." यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एम.जे. फेरवानी भी कहते हैं, "बाजार में तेजी न रहे, इसकी कोई वजह नहीं है." भविष्यवाणियां भी यही उम्मीद बंधाती हैं कि शेयर बाजार का मौजूदा उफान महज चार दिन की चांदनी साबित नहीं होगा. अरिधि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स के प्रबंध निदेशक राम के. पिपरैया कहते हैं, "मुझे उम्मीद है कि शेयरों की कीमतें अगले बजट तक बढ़ती ही रहेंगी. बीच में उतार-चढ़ाव चाहे हो."

फिर भी 1985 की भारी तेजी और उसके बाद 1986 की मंदी की याद अभी भी लोगों के दिल में ताजा है. बहुत से विशेषज्ञ इसे अभी भी एक सामान्य तेजी मान रहे हैं. चंपकलाल इन्वेस्टमेंट ऐंड फाइनांशियल कंसल्टेंसी लिमिटेड (सिफ्को) के उपाध्यक्ष भुपेन दलाल कहते हैं, "मैं नहीं समझता यह किसी भारी तेजी की शुरुआत है. यह तो महज बाजार के स्वस्थ होने की निशानी है क्योंकि वह अपने दुर्दिनों से मुक्त हो रहा है." जे.एम. फाइनांशियल के उपाध्यक्ष और बीएसई के पूर्व अध्यक्ष एम. कंपानी भी सहमति में कहते हैं, "बात सिर्फ इतनी है कि बाजार में गहमागहमी लौट आई है. लेकिन तेजी का रुझान तो है ही." इसकी कई वजहें भी हैं. बहुत से क्षेत्रों में कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास ठीक ढंग से चल रहा है, और सूखे के साल में अक्सर आने वाली मंदी टल चुकी है.

ज्यादातर विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि फरवरी-मार्च में शेयर बाजार एकदम डूब गया था. पिपरैया कहते हैं, "सरकार और समाचार माध्यम ने सूखे का असर शायद बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. इसलिए जब मामला साफ हुआ तो बाजार में तेजी आ गई."

इस मामले में सरकारी प्रवक्ता भी आशावादी हैं. वित्त मंत्रालय के निदेशक (निवेश) पी.आर. बिंदु माधवन कहते हैं, "शेयर बाजार के मौजूदा रुझान से यही जाहिर होता है कि पूंजी बाजारों की हालत सुधरी है और लगता यही है कि यह रुझान आगे भी बरकरार ही रहेगा."

अरसे बाद तेजड़ियों की निष्क्रियता टूटी. एकाएक उनके हरकत में आने से बाजार का रुख ही बदल गया. नया जोश, नई तेजी दिखाई देने लगी. और संकेत यही है कि यह तेजी बरकरार रहेगी

पर इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका सरकार द्वारा उद्योगों को दी गई रियायतों की भी रही. बहुप्रतीक्षित निवेश भत्ता (टैक्स बचाने और निवेश बढ़ाने की एक प्रमुख योजना) फिर से लागू की गई, निर्यात मुनाफों पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिए गए, ज्यादा उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया और फिर सरकार द्वारा कई दूसरी रियायतें दिए जाने की भी संभावनाएं हैं.

बहरहाल शेयर कीमतों की भारी तेजी से बहुत सारे छोटे निवेशक तो एकदम से हतप्रभ रह गए. वे या तो सुध-बुध खो बैठे या पागल-से हो गए. इसकी एक अहम वजह यह हो सकती है कि जब बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला हो गया तो बिकवाली लायक स्टॉक काफी कम था.

एक और वजह यह भी हो सकती है कि बाजार में अपनी-अपनी गोटियां भिड़ा रहे यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और व्यावसायिक बैंकों के हाल ही में बने पारस्परिक कोष जैसे दिग्गज संस्थानों ने तेजी से पहले ही बाजार का बहुत-सा कारोबार सोख लिया जिससे दूसरे खरीदार जब बाजार में पहुंचे तो उनके करने-धरने लायक वहां कुछ बचा ही नहीं था. साथ ही जब बाजार का रुख पलटा तो अभी तक जो बिकवाल थे वे भी खरीदार बनकर सामने आ गए. इससे बाजार में खरीदारी का ही बोलबाला हो गया. इसी का नतीजा है कि पिछले दो महीनों में बाजार में इस कदर नाटकीय ढंग से तेजी आई है.

दरअसल कुछ निवेश सलाहकारों का तर्क है कि छोटे निवेशक धीरे-धीरे सोच-समझकर ही बाजार की ओर रुख कर रहे हैं. कंपानी कहते हैं, "सिर्फ सयाने निवेशक ही वापस आ रहे हैं." शेयर बाजार के एक माहिर के मुताबिक, "छोटे निवेशकों का नजरिया भी अब बदल रहा है क्योंकि वेतनभोगी मध्यमवर्ग को खतरा उठाने की अपनी क्षमता का अंदाज हो गया है." फिलहाल तो नए शेयर जारी करने वाली कंपनियां ही अपनी तिजोरी भरने जा रही हैं.

1985 में शेयर बाजार ने जहां भारी मुनाफे के वायदे के साथ निवेशकों को ललचाया था, वहीं बाद के दो वर्षों में नुकसान के अंदेशे ने उनके होशो-हवास उड़ाए रखे. इस खेल के कुछ गुर सीखकर अब निवेशक खुद अपने बूते पर बाजार में पहुंचा है. फिलहाल स्थिति यही है.

—आनंद पी. रमन, बंबई में

महेंद्र कंपानी
उपाध्यक्ष, जे.एम. फाइनांशियल कंसल्टेंट्स

"सिर्फ सयाने निवेशक ही बाजार में वापस आ रहे हैं. बात सिर्फ इतनी है कि बाजार में गहमागहमी लौट आई है लेकिन तेजी का रुझान तो है ही"

भुपेन दलाल
उपाध्यक्ष, सिफ्को

"मैं नहीं समझता यह किसी भारी तेजी की शुरुआत है. यह तो महज बाजार के स्वस्थ होने की निशानी है क्योंकि वह अपने दुर्दिनों से मुक्त हो रहा है"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आल्विन-निशान

निशान बदलेगा

निजी कंपनी के हाथों बिकेगी

आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले तो दुपहिया वाहनों को निजी कंपनियों के हवाले किया, अब चौपहिया वाहनों की बारी लगती है. केंद्र सरकार जैसे स्कूटर्स इंडिया को राहुल बजाज को सौंपने की तैयारी कर रही है उसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार घाटे में चल रही दो सरकारी कंपनियों, आंध्र प्रदेश स्कूटर्स को दिल्ली के एस्कॉर्ट्स समूह को और आल्विन-निशान ट्रक कंपनी को बंबई की महिंद्रा ऐंड महिंद्रा को सौंपने के लिए प्रयासरत है. बल्कि राज्य मंत्रिमंडल ने तो जून के शुरू में यह फैसला कर लिया कि बीमार सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया जाए.

तेलुगु देशम सरकार का कहना है कि इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकती. व्यावसायिक इस्तेमाल के छोटे वाहन बनाने के लिए 1980 के प्रारंभ में जापानी सहयोग से चार कंपनियां बनाई गई थीं. उनमें से एक आल्विन-निशान भी है. ये चारों बाजार की मंदी, करों के बोझ और जापानी मुद्रा 'येन' के मुकाबले रुपए के मूल्य में भारी गिरावट की वजह से लागत मूल्य में बढ़ोतरी के चलते मुश्किल में ही चल रही हैं. बाकी तीन कंपनियां तो जैसे-तैसे अपना कारोबार चलाए जा रही हैं पर आल्विन-निशान तो पहले ही 10 करोड़ का घाटा उठा चुकी है. कारखाने से निकलने वाली प्रत्येक नई आल्विन कैबस्टार गाड़ी पर 20,000 रु. का घाटा हो रहा है. इस कंपनी के तेजी से घाटे में धंसते जाने के मुख्य तौर पर दो कारण हैं. एक तो, बिक्री निर्धारित लक्ष्य से काफी कम होने (1986-87 में 5117 बिक्री लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 950 और इस साल 1842 वाहनों की बिक्री) के कारण आयात खर्चे काफी बढ़ रहे हैं. और दूसरे, उत्पादन कम होने के कारण स्वदेशीकरण भी लाभकारी नहीं रहा है.

राज्य सरकार ने पहले तो सार्वजनिक उपक्रम प्रबंधन बोर्ड से इसे दुरुस्त करने की संभावनाएं तलाशने को कहा. बोर्ड ने सुझाया कि इसके लिए सरकार को बतौर शेयर और 5 करोड़ रुपए लगाने होंगे और विनिमय दर की अनिश्चितताओं तथा स्वदेशीकरण की समस्याओं को झेलना होगा. बोर्ड के महानिदेशक वाई. वेणुगोपाल रेड्डी ने कहा, "कुल 3956 कलपुर्जों में से 2692 पुर्जे देश में ही बन रहे हैं पर कम उत्पादन होने से लागत बढ़ गई है."

जब बोर्ड ने यह फैसला सुना दिया तब सरकार ने कंपनी को बेचने की बातचीत चलाने के लिए आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष भानु प्रसाद के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय समिति बनाई.

इस समिति ने मोदी, टीवीएस, अशोक लेलैंड और बजाज समेत कई प्रमुख उद्योग समूहों को इसे बेचने की पेशकश की. अंततः महिंद्रा समूह को ही चुना गया क्योंकि भानु प्रसाद के अनुसार, "हमें किसी ऐसे समूह की तलाश थी जो होड़ के डर से कंपनी को दो-एक वर्षों में ही बंद न कर दे." और महिंद्रा समूह ने सचमुच ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है. महिंद्रा के उप-प्रबंध निदेशक आर.के. पीतांबर ने कहा कि मंदी के बावजूद कंपनी सालाना 5,000 वाहन बेच सकती है, और वाहन को सस्ता बनाने के लिए कुछ फेरबदल किया जा सकता है. सरकार ने यह भी शर्त रखी है कि 806 कर्मचारियों में से एक की भी छंटनी नहीं होनी चाहिए और यह भी कि कंपनी को राज्य से बाहर नहीं ले जाया जाए.

इन सबके बावजूद भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ है. पूर्व इंका मंत्री तथा मजदूर नेता पी. जनार्दन रेड्डी का कहना है कि सरकार ने शुरू से ही कम पूंजी निवेश करके समस्या खड़ी की है. उन्होंने कहा, "इसमें सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही लगाए गए जबकि 52 करोड़ लगाने चाहिए थे." दूसरे लोगों का कहना है कि जब बिक्री बढ़नी शुरू हुई तभी कंपनी को बेचा जा रहा है.

लेकिन केंद्रीय उद्योगमंत्री जे. वेंगलराव ने राज्य सरकार के फैसले का समर्थन करके सबको चकित कर दिया. राव ने कहा,

निजीकरण के फैसले से तूफान खड़ा हो गया है. आलोचकों का कहना है कि जब बिक्री बढ़नी शुरू हुई तब कंपनी को बेचा जा रहा है

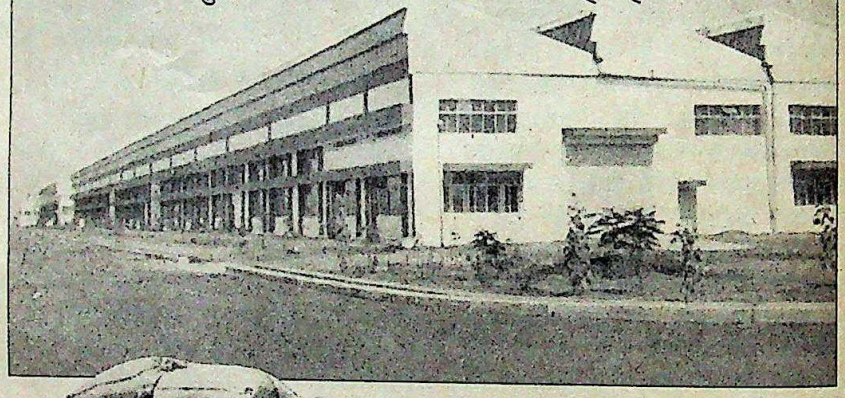

आल्विन कैबस्टार; और (ऊपर) इसका कारखाना

"बिक्री के खिलाफ किसी भी आंदोलन से मजदूरों का ही नुकसान होगा. इससे कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी. इसे महिंद्रा समूह के हाथों सौंपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच गया है."

दरअसल इस कंपनी के 26 प्रतिशत शेयरों को ही बेचा जा सकेगा और दूसरे 10 प्रतिशत शेयर हैदराबाद आल्विन के पास ही रहेंगे. पर बिक्री के लिए कंपनी की जापानी सहयोगी निशान (जिसके पास 15 प्रतिशत शेयर हैं) और 'एमआरटीपी' से मंजूरी लेनी पड़ेगी. चूंकि इसके 64 प्रतिशत शेयर पहले से ही निशान और आम लोगों के पास हैं इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह सही मायने में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है.

बहरहाल, इसकी बिक्री के मामले से यह पता चलेगा कि भारत में 'निजीकरण' का दौर दूसरे चरण में पहुंचेगा या नहीं.

—अमरनाथ के.मेनन और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विमान इंधन

करों से बढ़ी कीमत

विरोध जताने वाली विमानसेवाएं अब अपनी उड़ानें बंबई के बजाय दिल्ली से भरने और इंधन खाड़ी के किसी हवाई अड्डे से लेने पर विचार कर रही हैं. अगर ऐसा हो गया तो इससे भारतीय पर्यटन और तेल उद्योग को गंभीर नुकसान हो सकता है .

इस घोषणा से उड्डयन अधिकारियों में खलबली मचनी ही थी. विमान इंधन पर 25 फीसदी कर बढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से नाराज कुछ विदेशी विमानसेवाओं ने बंबई हवाई अड्डे से अपनी उड़ानें समाप्त करने की धमकी तक दे डाली. यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों के 12 राजदूतों ने इसके खिलाफ मुहिम ही छेड़ दी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कड़ा विरोध व्यक्त किया. पश्चिम जर्मनी के अधिकारियों ने तो इस मामले को उस समय उठा दिया जब हॉल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां दौरे पर थे.

कर बढ़ाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने 16 मार्च की रात को किया. इससे राज्य सरकार को 51 करोड़ रु. की सालाना आमदनी होगी. यानी बंबई में इंधन दुनिया भर से महंगा हो गया. यहां एक गैलन इंधन (4.54 लिटर) की कीमत अब 1.26 डॉलर है जबकि सिंगापुर में 52 सेंट, बैंकॉक में 59 सेंट और लंदन में 57 सेंट है.

विदेशी विमानसेवाओं के अधिकारी इसलिए भी ज्यादा नाराज हैं क्योंकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के समझौते पर दस्तखत कर रखे हैं जिसके तहत इंधन पर कर लगाना वर्जित है. लेकिन राज्य के वित्त राज्यमंत्री श्रीकांत जिचकर इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहते हैं कि 1958 के बंबई स्प्रिट एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार को इस तरह का कर लगाने का पूरा अधिकार है.

विमानसेवाओं के प्रतिनिधियों की समिति के अध्यक्ष फ्रांसिस दा गामा राज्य सरकार के इस दावे का खंडन करते हैं कि वह हर साल इंधन पर कर लगाने से बचती रही है. जिचकर सफाई में कहते हैं कि अब तक केंद्र राज्य सरकार की इस मद में भरपाई कर रहा था. लेकिन 450 रु. प्रति किलोलिटर का मुआवजा राज्य सरकार की 805 रु. के मुआवजे की मांग से बेहद कम है. वे कहते हैं, "मैं तो सभी विमानसेवाओं की मदद करना चाहता हूं लेकिन महाराष्ट्र के गरीबों की कीमत पर कतई नहीं."

यानी अंतत: इसकी कीमत तेल, पर्यटन और निर्यात से जुड़े महकमों को ही चुकानी पड़ेगी. केंद्र से विरोध व्यक्त करने वाली 19 विमानसेवाओं में से ज्यादातर अब अपनी उड़ानें बंबई के बजाय दिल्ली से करने और खाड़ी के किसी हवाई अड्डे से इंधन लेने पर विचार कर रही हैं. ब्रिटिश एअरवेज जहां दिल्ली स्थानांतरण के बारे में सोच रही है, वहीं स्विसएअर भारत में इंधन न खरीदने का इरादा कर रही है. आस्ट्रेलियाई क्वांटास ने नवंबर से भारत की अपनी सभी उड़ानें रद्द करने का फैसला कर लिया है जबकि एअर कनाडा अपने चालक दल को दुबई में टिकाने की सोच रही है. वैसे यह कोई आसान बात नहीं है.

इन सब बातों से बहुत लोग चिंतित हैं. ओबेराय होटल समूह के उपाध्यक्ष अनिल मधोक को डर है कि विमानसेवाएं जितना भारत में कमाएंगी उसका बहुत कम हिस्सा

बंबई हवाई अड्डे पर खड़े विमान : कड़ा विरोध

ही अब यहां खर्च करेंगी. वे बताते हैं कि मध्यम दर्जे की विमान सेवा अकेले बंबई के ओबेराय होटल में ही एक साल में चार करोड़ रुपए खर्च कर देती है.

विमानसेवा कंपनियों की जवाबी कार्रवाई से घरेलू उद्योग को कितना नुकसान पहुंच सकता है इसका आभास पिछले पखवाड़े तब हुआ जब उन्होंने इस बढ़े हुए कर की वसूली, माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ाकर करने का फैसला कर लिया. इसकी वजह से विश्व बाजार में महाराष्ट्र से निर्यात होने वाला माल महंगा हो गया.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को डर है कि उसके विमान इंधन की बिक्री (सालाना 100 करोड़ रु.) में गिरावट आएगी. इंडियन ऑयल के उड्डयन प्रबंधक आई.वी. के. मूर्ति कहते हैं, "अगर बड़ी विमानसेवाओं ने अपनी उड़ानें खत्म कीं तो हमारे व्यापार पर इसका जरूर असर पड़ेगा."

लेकिन एअर इंडिया इंडियन ऑयल से कहीं ज्यादा चिंतित है. इसके वित्त निदेशक सुभाष गुप्ते कहते हैं, "हमें इस कर की वजह से सालाना 18 करोड़ रु. अतिरिक्त अदा करने होंगे." ईंधन की वजह से एअर इंडिया भी दिल्ली में अपनी और ज्यादा उड़ानों के पड़ाव बनाने पर सोच-विचार कर रही है.

बहरहाल, इसकी वजह से केवल एक फायदा यह हो सकता है कि बंबई हवाई अड्डे पर बोझ घटेगा. अभी हफ्ते में यहां 304 उड़ानें ठहरती हैं. और 283 उड़ानें भरी जाती हैं.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किर्लोस्कर घराना

उबरने की अनूठी मिसाल

अपने शताब्दी वर्ष में घराने की स्थिति सुधरने के आसार

एक बड़ा इंजीनियरिंग समूह खरीदिए, ऊपर बैठे प्रबंध निदेशकों को हटा दीजिए और उनकी जगह 25-35 साल के बीच के नौजवानों को ले आइए. फिर उसे बाजार की भयंकर मंदी में झोंक दीजिए जिससे समूह की कंपनियों को भारी नुकसान हो. सोने में सुहागा यह कि सरकार से समूह की कंपनियों पर सुर्खियों में आने वाले छापे डलवाइए. तब देखिए कैसे समूह में संकट और पैसे की बेमिसाल कमी होने के साथ-साथ नई परियोजनाएं रुक जाती हैं. कुल मिलाकर इसी को कहते हैं अस्तित्व बचाने की लड़ाई.

ठीक यही हालत पिछले कुछ वर्षों से किर्लोस्कर समूह की हुई है. इस समय समूह को संकट से उबारने की कोशिश के अगुआ हैं 85 वर्षीय एस.एल. किर्लोस्कर. उन्होंने एक तरह से समूह के कामकाज से आधा अवकाश ग्रहण कर लिया था. लेकिन किर्लोस्कर वंश की लगभग एक पीढ़ी की असामयिक मौत हो जाने के कारण उन्हें कामकाज में फिर पूरी रुचि लेनी पड़ी और अपने पोतों और भतीजे को कुशल बनाने में जुट जाना पड़ा.

700 करोड़ रु. के कारोबार वाले इस इंजीनियरिंग समूह के शताब्दी वर्ष में अब किर्लोस्कर घराना आखिर थोड़ी-बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है. पहले कभी शायद ही मुनाफा देने वाली दो कंपनियों (किर्लोस्कर ब्रदर्स और किर्लोस्कर न्यूमेटिक जिन्होंने दो साल तक लाभांश नहीं दिया) की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी हो गई है. दूसरी दो इकाइयां (किर्लोस्कर ऑयल इंजंस और मैसूर किर्लोस्कर) भी नुकसान से उबर रही हैं लेकिन समूह की छह प्रमुख कंपनियों में से दो (किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक और किर्लोस्कर क्यूमिस) हमेशा अच्छी स्थिति में रही हैं.

किर्लोस्कर समूह में संकट उस वक्त पैदा हुआ जब 1982 और 1985 के बीच एस. एल. किर्लोस्कर के दो बेटों और सबसे छोटे भाई की मृत्यु हो गयी जिससे अप्रत्याशित रिक्तता पैदा हो गई. 1985 में वी.पी. सिंह ने भी इस समूह पर अपने प्रसिद्ध छापे डलवाए थे और लगभग उसी समय इंजीनियरिंग उद्योग में मंदी छा गई थी.

लेकिन अब युवा किर्लोस्कर पीढ़ी—विजय (37), अतुल (32), संजय (31) और विक्रम (29) ने समूह की ज्यादातर प्रमुख कंपनियों का कामकाज पुख्तगी से संभाल लिया है. 1985 के छापों के बाद करों के जो मामले बने थे, कुछ वे भी उन्होंने जीत लिए हैं. बाकी मामले भी समय पर सुलट जाने की उन्हें उम्मीद है. एस.एल. किर्लोस्कर कहते हैं, "मुझे खुशी है कि वे (पोते और भतीजा) शानदार काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ सही कदम बढ़ा रहा हूं."

इस समूह में संकट उस समय पैदा हुआ जब 1982 और 1985 के बीच एस.एल. किर्लोस्कर के दो बेटों और सबसे छोटे भाई की मृत्यु हो गई

कंपनी के पुणे स्थित मुख्य कार्यालय में बैठे ये प्रसन्नता से कहते हैं, "अब मेरा लक्ष्य अवकाश ग्रहण करना है. मैं 20 वर्षों से अवकाश ग्रहण करने की निरंतर कोशिश करता आ रहा हूं!"

इस दशक के सबसे मुश्किल भरे वर्षों के दौरान समूह में उस समय अनबन भी हो गई थी जब परिवार की दो शाखाओं के सदस्यों को समूह की मुख्य कंपनियों से हटाकर उन्हें एक छोटी कंपनी लकाकी पेंट्स सौंप दी गई थी. हालांकि इसकी वजह से परिवार में फैले असंतोष के बारे में पुणे में कुछ चर्चा होती रही है, लेकिन एस.एल. किर्लोस्कर ने युवा किर्लोस्कर के मुताबिक अच्छा कामकाज न करने वाले परिवार के दो सदस्यों को प्रबंधन से हटाया था.

अपने बेटों और भाई की असामयिक मौत के बाद एस.एल. किर्लोस्कर ने अगली नौसिखुआ पीढ़ी पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उनसे कहा, "मैं नहीं जानता कि और कितने सा

(बाएं से) विजय, संजय, एस.एल. किर्लोस्कर, विक्रम और अतुल: नई पीढ़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिंदा रहूंगा. मेरे सीने में एक टाइम बम (पेसमेकर) है. और मैं चाहता हूं कि तुम लोग ही कंपनियों को चलाओ. अगर मेरी सलाह नहीं चाहिए तो मत लेना. पर कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे दोष मत देना."

यह व्यवस्था अच्छी तरह काम करती दिखती है. किर्लोस्कर घराने की एक पीढ़ी भले ही खत्म हो गई हो लेकिन यह ऐसा मामला है जिसमें पीढ़ी का अंतर नहीं है. युवा किर्लोस्कर पीढ़ी (सभी विनम्र, प्रशिक्षित इंजीनियर और अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं) समूह के 85 वर्षीय अध्यक्ष को ऐसा पथ-प्रदर्शक मानती है जो उन्हें नैतिक समर्थन देता है, उनका मनोबल बढ़ाता है, सही सवाल पूछता है और सलाह देने के लिए उपलब्ध रहता है. संजय किर्लोस्कर (जो किर्लोस्कर ब्रदर्स में पंप, वाल्व, और मशीनों के कलपुर्जे बनाते हैं) कहते हैं कि एस.एल. किर्लोस्कर उन सबके धर्मपिता जैसे हैं. किर्लोस्कर ऑयल इंजंस के अतुल कहते हैं कि वे सीधे-सादे और आश्चर्य-जनक समाधान सुझाते हैं और विक्रम (जो फाउंड्री व मशीन टूल इकाइयों वाली मैसूर किर्लोस्कर चलाते हैं) कहते हैं कि बोर्ड की बैठकों में एस.एल. किर्लोस्कर "हमेशा ऐसे सवाल पूछते हैं, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती."

समूह के अध्यक्ष खुद कहते हैं कि वे सब गंभीर संकट में नहीं पड़े होते अगर उनके अपने दोनों बेटों (चंद्रकांत और श्रीकांत) की जल्दी-जल्दी मौत न हुई होती और भाई रविकांत उनसे थोड़े दिन पहले न गुजरे होते.

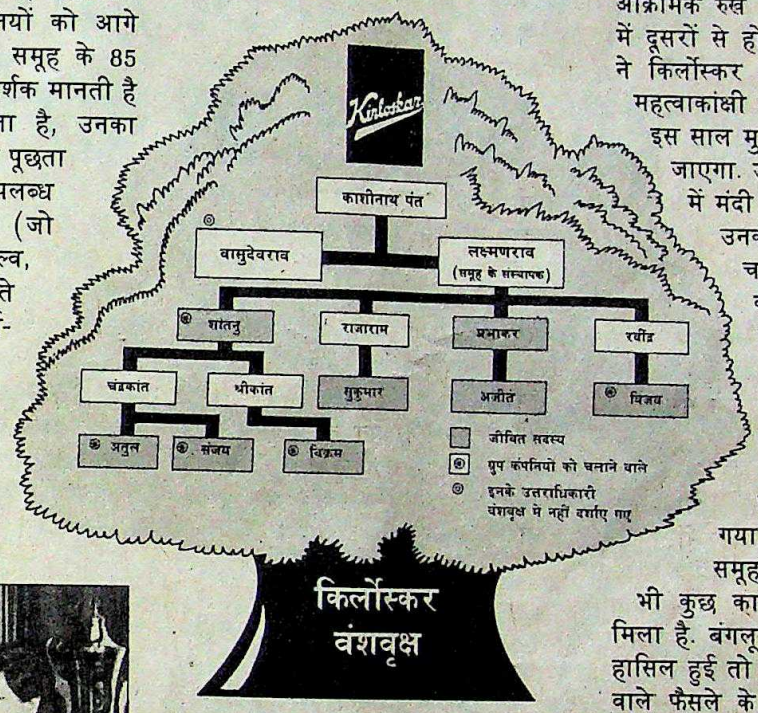

किर्लोस्कर वंशवृक्ष

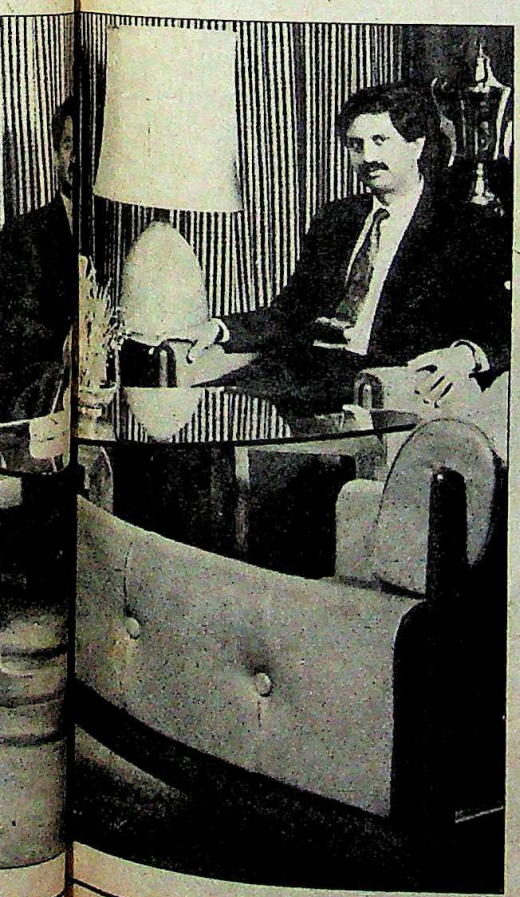

लेकिन घराने के नौजवान इसे दूसरे नजरिये से देखते हैं. जैसा कि पिछले पखवाड़े अतुल ने बताया, "पर हमने कुछ समस्याओं से अक्सर उन्हें अलग रखने की कोशिश भी की."

एक मायने में समस्याएं उत्तराधिकार के सवाल से शुरू हुईं. इसके अलावा पुराने और वरिष्ठ कर्मचारियों से निबटने की भी समस्या थी. विक्रम कहते हैं, "जिस आदमी ने आपको बचपन से खिलाया-दुलारा हो उसे आप क्या कह सकते हैं?"

किर्लोस्कर घराने के सामने सबसे बड़ी समस्या शायद नकदी की थी. अतुल कहते हैं कि माल सप्लाई करने वालों को अक्सर समय पर भुगतान नहीं किया जाता था. संजय याद करते हैं कि उन्हें कई बार माल सूची में कटौती करनी पड़ती थी, बहुत जरूरी चीजें ही खरीदी जाती थीं. और विक्रम पूंजी को तेजी से फैलाने की महत्ता जानने के बारे में बताते हैं. ज्यादातर युवा किर्लोस्कर कहते हैं कि उन्होंने बुनियादी सबक यह सीखा है कि नकदी का बेहतर प्रबंध किया जाए.

आज किर्लोस्कर घराने की नकदी की स्थिति निस्संदेह पहले से बेहतर है और युवा किर्लोस्कर पीढ़ी की पकड़ मजबूत हो गई है.

विजय बताते हैं कि इस तरह पिछले नौ साल में किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक के सामान की बिक्री चार गुना बढ़ी है. संजय के तहत किर्लोस्कर ब्रदर्स के बारे में माना जाने लगा है कि उसकी तो काया ही पलट गई है. मरणशैया पर पड़ी न रहकर उसने अब आक्रामक रुख अपना लिया है और बाजार में दूसरों से होड़ लेने लगी है. और अतुल ने किर्लोस्कर ऑयल इंजंस के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं जिन पर इस साल मुनाफा कमाते ही अमल किया जाएगा. उधर विक्रम मशीन उपकरणों में मंदी से जूझ रहे हैं जिसके कारण उनकी मैसूर किर्लोस्कर घाटे में चल रही है. लेकिन उन्होंने कंपनी को व्यवस्थित करने के लिए बहुत परिश्रम किया. कर्मचारियों की संख्या में 1,000 की कटौती की गई, टैक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण किया गया, माल-प्रबंधन में फेरबदल किया गया, विपणन नीति बदल दी गई. समूह को कर संबंधी मामलों में भी कुछ कामयाबी मिलने से प्रोत्साहन मिला है. बंगलूर वाले मुकदमे में एक जीत हासिल हुई तो पुणे में दूसरी (हालांकि पुणे वाले फैसले के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है). दूसरे मुकदमे अभी अदालतों में हैं. एस.एल. किर्लोस्कर कहते हैं, "हमने अभी तक सरकार को धेला नहीं दिया है. हां, मुकदमों में खूब पैसा बहाया है."

यह समूह कर संबंधी मुकदमों में जूझने, नकदी की कमी को दूर करने और बाजार में गिरावट से उबरने के प्रयास में इस कदर व्यस्त रहा है कि बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए न तो इसके पास पैसा रहा और न ही ताकत. और फिर किर्लोस्कर घराना नेताओं का भी कभी करीबी नहीं रहा है. एस.एल. किर्लोस्कर के धुर-दक्षिणपंथी विचारों और व्यापार पर हर तरह के नियंत्रण की खुली मुखालफत के कारण यह समूह सरकार का कृपापात्र नहीं बन पाया. नतीजतन इसने जब औद्योगिक लाइसेंसों की मांग भी की तो उसे अमूमन वे मिल नहीं पाए. विजय कहते हैं, "एक समय तो हम सोचते थे कि हम लाइसेंसों के लिए आवेदन करें भी तो हमें नहीं मिलेंगे. इसलिए परेशान क्यों हों? इससे ठहराव आ गया. अब हमारा नजरिया बदल गया है."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बेशक, हम अपने माता-पिता की चिंता तो करते हैं पर ऐसे मौके कितने होते हैं जब हम इसे जाहिर भी करते हों?

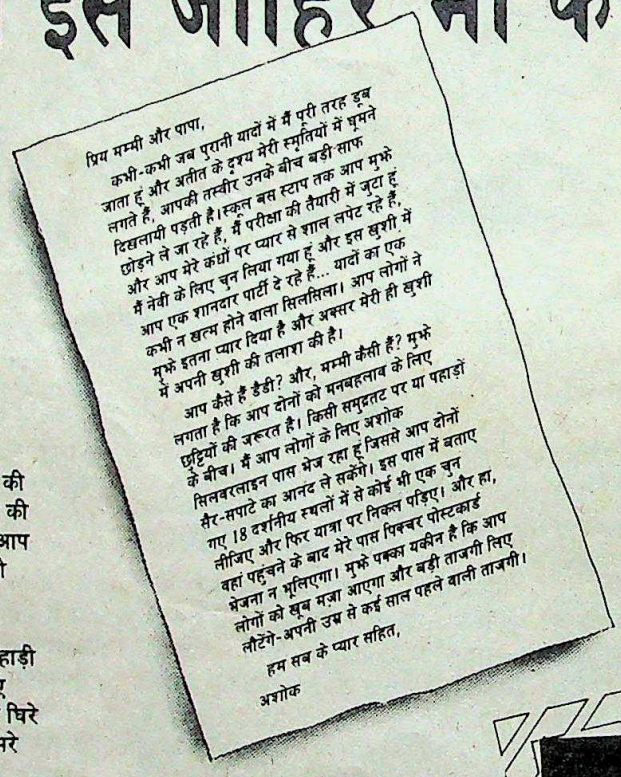

अशोक सिल्वरलाइन पास

अपने माता पिता को या 55 वर्ष से अधिक की आयु के अपने किसी प्रियजन को सप्ताहांत की छुट्टियों के लिए इसे भेंट में दीजिए। अगर आप इस उम्र तक पहुंच गए हैं तो क्यों न खुद ही इसका आनंद उठायें। दो दिनों के लिए-शनिवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक। वन्य जीवों से भरे पहाड़ी सैरगाह में, अतीत की शान शौकत के लिए मशहूर किसी शहर में या खजूर के पेड़ों से घिरे किसी सागर तट पर। एक रात के लिए कमरे का खर्च महज 100 रुपये।

15 अप्रैल से 30 सितम्बर 88 तक वैध

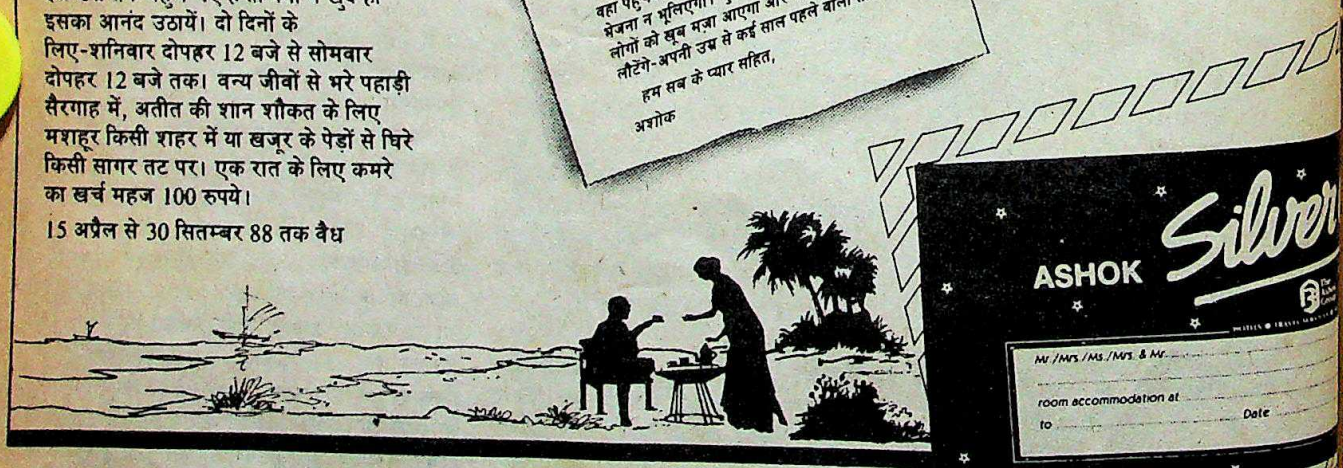

• 55 वर्ष से अधिक की आयु के केवल भारतीय नागरिकों के लिए • व्यवसाय से संबंधित यात्रा पर नहीं लागू • अनुरोध पर आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी • जहां लागू हैं, वहां कर अतिरिक्त • स्थानीय निवासियों का स्वागत है।

यह योजना अशोक ग्रुप के निम्नांकित होटलों में उपलब्ध है:

आगरा अशोक; औरंगाबाद अशोक; होटल अशोक, बंगलोर; भरतपुर फारेस्ट लॉज; कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर; अशोक ट्रेवलर्स लॉज, बोधगया; एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता; हसन अशोक; जयपुर अशोक; जम्मू अशोक; खुजराहो अशोक; कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट; मुदुरै अशोक; टेम्पुल बे अशोक बीच रिसोर्ट, ममल्लपुरम; ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर; लोदी होटल, होटल रंजीत (शुद्ध शाकाहारी), नयी दिल्ली; पाटलिपुत्र अशोक, पटना; वाराणसी अशोक.

जानकारी और बुकिंग के लिए किसी भी अशोक ग्रुप होटल या अशोक नेटवर्क सर्विस से यहां संपर्क करें:- बम्बई (फोन: 2026481, 2026022), कलकत्ता (फोन: 435208, 435264), दिल्ली (फोन: 600121, 600412), मद्रास (फोन: 473078, 472186), बंगलोर (फोन: 79411, 73894).

The Ashok Group

HOTELS • TRAVEL SERVICES • DUTY FREE SHOPS

India Tourism Development Corporation

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसलिए अतुल किर्लोस्कर चार सीटों वाला विमान बनाने की परियोजना स्थापित करने के पीछे पड़े हैं; किर्लोस्कर क्यूमिंस के अरुण किर्लोस्कर हंगरी के सहयोग से ट्रक बनाने की एक परियोजना को सरकारी मंजूरी मिलने की आस लगाए बैठे हैं; और विक्रम फायदेमंद फाउंड्री व्यवसाय में और ज्यादा पूंजी लगाने की बात करते हैं. इस बीच विजय इस समूह की कुछ छोटी कंपनियों को फिर से व्यवस्थित करने और उनमें नई जान फूंकने के प्रयास में जुटे हैं.

हाल के वर्षों में किर्लोस्कर की कई नई परियोजनाएं धीमी गति से चलती रही हैं. इसकी एक वजह तो अक्सर नकदी की कमी रही है और दूसरी (जैसा कि किर्लोस्कर न्यूमेटिक के प्रबंध निदेशक पी.डी. गुणे बताते हैं) समूह का वह सिद्धांत है जिसके मुताबिक छोटे से शुरू करो और फिर आगे बढ़ो. समूह की ज्यादातर प्रमुख कंपनियां इसी तरह शुरू हुईं. दरअसल 100 साल पहले लक्ष्मणराव किर्लोस्कर ने साइकिल की मरम्मत से शुरुआत करके किर्लोस्कर इंटर-प्राइजेज स्थापित की थी. इसके बाद उन्होंने फौलाद के हल बनाने का काम शुरू किया. उस समय यह एक क्रांतिकारी उत्पादन था क्योंकि तब सभी तरह हल केवल लकड़ी के ही बना करते थे.

इन दिनों यह समूह यूरोप और अमेरिका की उन कंपनियों के साथ जुड़ने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है जो अपने उत्पादों (डीजल इंजन, मशीनी कलपुर्जे और बिजली की मोटरें आदि) को भारत में सप्लाई करने के लिए किसी माध्यम की तलाश में हैं. एस.एल. किर्लोस्कर का मानना है कि भारत में लागत संबंधी कई रियायतें हैं और हमारा समूह इन सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय उत्पादन करता है. वे कहते हैं, "इस क्षेत्र में उत्पादन का हमारा बहुत पुराना अनुभव रहा है."

अतुल का मानना है कि समूह को पहले जैसी नकदी की समस्या से भविष्य में दो चार नहीं होना पड़ेगा, "पहले तो हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी कर्ज मांगने नहीं जा सकते थे. वे कहते कि मेरी कंपनी घाटे में चल रही है और मेरे पास न तो अनुभव है, न कोई पिछला उल्लेखनीय रिकार्ड. लेकिन अब हमारी जरूरतें तो और ज्यादा बढ़ गई हैं."

यह समूह अपनी मुश्किलों पर जहां धीरे-धीरे काबू पाता जा रहा हैं, वहीं लगता है कि उसका शताब्दी वर्ष उसके लिए एक नए बदलाव का मोड़ साबित होगा.

—टी.एन. नैनन, पुणे में

किल्लिक निक्सन

कानूनी कार्रवाई

'फैक्स' के प्रयोग पर विवाद

इंजीनियरिंग और पेंट्स की दुनिया की दिग्गज, 130 वर्ष पुरानी किल्लिक निक्सन कंपनी ने जब अपनी संचार व्यवस्था के विज्ञापन के लिए बंबई में बड़े-बड़े बोर्ड लगवाए तो ग्राहकों का ही नहीं, कुछ और लोगों का भी ध्यान उनकी ओर गया. टेलीफोन विभाग ने करीब एक साल बाद अदालती नोटिस भिजवा दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि वह निजी लाभ के लिए दूरसंचार व्यवस्था का गैरकानूनी इस्तेमाल कर रही है.

विज्ञापन बोर्डों में कहा गया था कि किल्लिक निक्सन (1987 का कारोबार 100 करोड़ रु.) की फेसीमाइल ट्रांसीवर (फैक्स) व्यवस्था भाड़े पर उपलब्ध है और इससे विदेशी ठिकानों पर भी संदेश भेजे जा सकते हैं. बस चूक यहीं हो गई क्योंकि इससे महानगर टेलीफोन निगम (मटेनि) लिमिटेड को निक्सन पर भारतीय टेलीग्राफिक नियमों की धारा 429 और 429 (ए) के उल्लंघन का मामला चलाने का मौका मिल गया. इन धाराओं के मुताबिक टेलीफोन यंत्र निजी इस्तेमाल के लिए होता है. यदि कभी कोई बाहरी व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करे तो उससे सार्वजनिक दर से ज्यादा पैसा नहीं वसूला जा सकता.

टेलीफोन निदेशिका से भी छोटे आकार की फैक्स मशीन पत्रों, नक्शों, चित्रों, सरीखे दस्तावेजों को महज एक टेलीफोन के सहारे इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में तब्दील करके भेज देती है. दूसरी तरफ किसी टेलीफोन यंत्र से जुड़ी मशीन एक मिनट से भी कम समय में दस्तावेज की फोटो प्रतिलिपि तैयार कर देती है. देश के भीतर इस व्यवस्था से एक बार संदेश भेजने की कीमत एक एसटीडी कॉल के बराबर है.

किल्लिक निक्सन की तरह यह सेवा उपलब्ध कराने वाली करीब 300 कंपनियां हैं. 'मटेनि' ने निक्सन के भारी-भरकम विज्ञापन (महत्वपूर्ण जगहों पर लगे विज्ञापन बोर्डों पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए) की वजह से ही इसके खिलाफ कार्रवाई की. अधिकारियों ने कंपनी को फंसाने के लिए सबसे पहले एक ग्राहक भेजा जो एक दस्तावेज दिल्ली भिजवाना चाहता था. अधिकारियों का कहना है कि इसमें 30 सेकेंड का वक्त लगा जिसके लिए 9 रुपए वसूलने चाहिए थे. लेकिन कंपनी ने 60 रु. का बिल थमा दिया. इसके तुरंत बाद 'मटेनि' ने अदालत में मामला दाखिल कर दिया. निगम ने यह भी दलील दी कि कंपनी का सालाना टेलीफोन बिल 3,000 रु. होता था जो इस यंत्र के लगाने के बाद 2.5 लाख रु. हो गया है. पिछले पखवाड़े अदालत ने इसकी फैक्स मशीन जब्त करने का आदेश जारी कर दिया.

टेलीफोन विभाग ने किल्लिक निक्सन पर निजी लाभ के लिए दूरसंचार व्यवस्था के गैरकानूनी इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

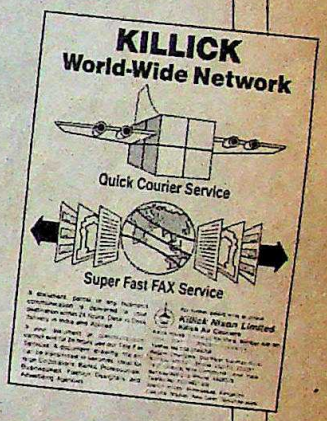

फैक्स का विज्ञापन

लेकिन निक्सन ने भी अपने हथियार अभी नहीं डाले हैं. इसकी कूरियर सेवा के अध्यक्ष टी.बी. पटेल कहते हैं कि दिल्ली वाले उस कॉल में 87 सेकेंड का वक्त लगा था. प्रति दो सेकेंड की कॉल पर 1.25 रु. के हिसाब से 55 रु. बनते हैं. इसके अलावा बाकी खर्चे भी हैं.

दूसरी कंपनियों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के नेशनल थर्मल ने भी फैक्स का विज्ञापन जारी किया और अपने सलाहकारों, ठेकेदारों व बैंक को सुविधा मुहैया कराता है. पटेल पूछते हैं, "क्या ये सलाहकार बाहरी नहीं माने जाएंगे?" 'मटेनि' के उप-महाप्रबंधक इसके जवाब में कहते हैं, "किल्लिक निक्सन ने तो दरअसल ग्राहकों को पटाने की कोशिश की." पर 'मटेनि' के अधिकारियों का तर्क जायज नहीं लगता.

बहरहाल, जब तक इस नई तकनीक के बारे में नीतिगत फैसला नहीं हो जाता तब तक फैक्स मशीन रखने वालों की हालत वेश्या सरीखी ही बनी रहेगी. छिपकर जो चाहे कर लें.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

तेजी का मिजाज

मगर अस्थायी गिरावट भी

यह तेजी के साथ-साथ अस्थायी मंदी का भी दौर रहा. पिछले पखवाड़े शेयर बाजार का यही सबक था. शेयरों की कीमतें तेजी से चढ़ीं फिर एकाएक लुढ़कने लगीं. लिहाजा ज्यादातर शेयर कुल मिलाकर घाटे में रहे.

पर बाजार का मिजाज तेजी का ही है. इकॉनॉमिक टाइम्स का शेयर मूल्य सूचकांक हालांकि इस साल 8 जून को सर्वाधिक 272.2 पर पहुंचकर दो हफ्ते में ही लुढ़ककर 256.8 पर आ गया. लेकिन यह गिरावट पहले अचानक आई तेजी के बाद हुआ अस्थायी 'सुधार' ही है.

यह 'सुधार' उतना गंभीर नहीं होता यदि इसके पीछे केंद्र की अनिश्चितता के साथ ही वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी (जो शेयर बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं) को हटाए जाने का अंदेशा काम न कर रहा होता. शेयर कीमतों में गिरावट की एक वजह यह भी रही कि बाजार के कर्ता-धर्ताओं ने खरीदारों पर भारी 'पड़ता' थोप दिया और दलालों पर अपनी खरीद को बिकवाली में लाने के लिए दबाव डाला.

चार्ट: बी.के. शर्मा

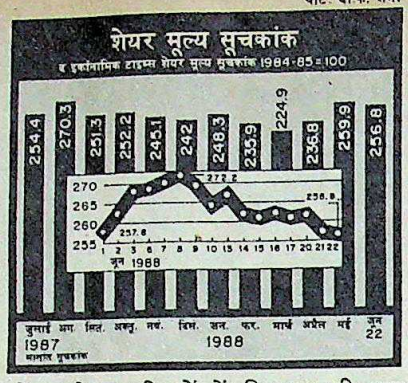

इसकी मार टाटा इंजीनियरिंग (जिसकी बिक्री, मुनाफे और लाभांश में खासी वृद्धि हुई) सरीखी कंपनी को भी झेलनी पड़ी. इसके शेयर जिस कीमत (670 रु.) से चढ़ना शुरू हुए, लौटकर वहीं पहुंच गए. बावजूद इसके कि भारी वाहनों के बाजार में तेजी का रुझान था.

इसलिए पिछले पखवाड़े के शेयर चार्टों में दिखी मंदी भ्रामक है. दरअसल मई के आखिर में शेयर मूल्य सूचकांक पिछले अगस्त के बाद सबसे ऊंचा रहा. अब ठीक-ठाक मानसून के कारण अच्छी फसल के आसार, कंपनियों की लगातार बेहतर वित्तीय कामयाबियों की रिपोर्टों और सरकार द्वारा लगातार उदार नीतियां लागू किए जाने से बाजार में तेजी और उत्साह का महौल है. कई महीनों बाद निजी निवेशक बाजार में दिखने लगे और खरीद वित्तीय संस्थानों तक ही सीमित नहीं रही.

इस बीच आकर्षण का केंद्र रिलायंस ही बना हुआ है. इसने इधर कई रियायतें बटोरी हैं. और निवेशक भी इतना मतलब अच्छी तरह समझ गए हैं. कंपनी के 500 करोड़ रु. से भी ज्यादा के डिबेंचर जल्दी ही बाजार में आने की उम्मीद से उसकी शेयर की कीमतों का चढ़ना तय है.

संभावना है कि जब बाजार का अति उत्साह कुछ ठंडा पड़ेगा और उसके कर्ता-धर्ताओं द्वारा संतुलित रवैया अपनाने से खरीदारों पर भारी पड़ते का बोझ उठेगा तो व्यावसायिक इलाकों में स्वाभाविक खुशी की वही लहर दौड़ जाएगी जो पिछले कुछ हफ्तों में दिखाई पड़ी थी. कोई अनहोनी ही तेजी के इस रुझान को रोक सकती है.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	नीचा	बंद 6.6.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	40.00	30.25	37.50	1.75 —
एसोसिएटेड सीमेंट	265.50	128.50	211.00	43.00 —
एटलस कोप्को	63.50	32.50	47.00	9.00 —
एशियन पेंट्स	175.00	128.75	152.50	16.25 —
बजाज ऑटो	520.00	187.50	242.50	38.75 +
बड़ौदा रेयॉन	282.50	140.00	222.50	22.50 —
बाटा इंडिया	77.25	50.50	72.75	8.00 +
भारत फोर्ज	147.00	101.00	128.00	18.00 —
बिरला जूट	47.00	32.25	41.00	4.00 —
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	37.00	5.00 —
बॉम्बे डाइंग	159.50	94.00	139.00	5.50 —
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	87.00	4.00 —
बुक बांड	98.00	75.00	87.00	6.50 —
सेंचुरी स्पिनिंग	875.00	617.50	785.00	72.50 —
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	66.50	3.00 —
कोलगेट	222.50	160.00	215.00	3.30 —
सायनामिड	52.00	33.00	43.00	8.00 —
डीसीएम	47.00	28.00	44.00	—
डनलप	86.50	69.50	76.00	5.00 —
ईआई होटल्स	54.00	38.00	50.00	1.00 —
एस्कार्ट्स	57.00	37.00	47.00	6.50 —
फिनोलेक्स केबिल्स	418.75	272.50	390.00	18.75 —
फूड स्पेशलिटीज	142.00	93.50	119.00	16.00 —
गरवारे नाइलोन	43.00	20.00	39.00	1.00 —
जी.ई. शिपिंग	33.75	20.80	29.00	4.00 —
गुजरात स्टेट फर्टि.	140.00	75.00	122.00	16.00 —
ग्रासिम इंडिया	105.00	81.50	96.00	8.50 —
हिंदुस्तान सिबा	520.00	332.50	460.00	20.00 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	85.00	2.00 —
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	82.00	4.50 —
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	65.00	9.00 —
हिंदुस्तान मोटर्स	27.00	15.80	23.80	2.50 —
आई.ई.एल.	43.75	31.00	37.50	3.75 —
इंडियन आर्गेनिक	27.00	15.00	20.00	6.50 —
इंडियन रेयॉन	75.00	46.00	70.00	4.00 +
इंडाल	223.75	133.75	170.00	10.00 —
इंगरसॉल-रैंड	335.00	205.00	247.00	38.00 —
आई.टी.सी.	46.00	30.00	41.25	3.25 —
जे.के. सिंथेटिक्स	74.00	45.50	64.50	3.50 —
काइनेटिक इंजी.	285.00	161.25	225.00	—
किर्लोस्कर क्युमिस	59.00	48.00	55.00	—
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	250.00	35.00 —
लारसन-टुब्रो	101.50	75.50	92.00	5.00 —
लिप्टन	67.00	52.00	62.00	3.50 —
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	15.00	4.50 —
मधुरे कोट्स	77.00	59.00	68.50	0.75 —
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	48.50	54.50	5.50 —
मिल्क फूड	140.00	72.50	115.00	5.00 —
मोटर इंडस्ट्रीज	630.00	447.50	570.00	52.50 —
मुकुंद आयरन	97.00	72.50	86.50	9.50 —
नेशनल आर्गेनिक	525.00	390.00	475.00	—
निरलॉन	16.00	5.00	10.50	2.50 —
ओरके सिल्क मिल्स	51.00	17.00	38.00	12.50 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	161.25	180.00	15.00 —
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	37.00	24.50	33.00	1.50 —
फाईजर	79.50	50.00	64.00	4.00 —
प्रीमियर ऑटो	39.50	23.00	37.00	0.50 +
रैनबेक्सी	120.00	72.50	77.00	35.50 —
रेमंड	86.00	41.50	49.50	1.00 —
रॉकिट ऐंड कोलमैन	227.00	175.00	213.00	3.00 —
रिलायंस इंडस्ट्रीज	213.00	69.00	201.50	11.50 —
शॉ वैलेस	132.00	50.50	55.00	4.00 —
श्रीराम फाइबर्स	62.50	32.50	54.00	1.00 —
सीमेंस इंडिया	80.00	56.00	65.00	7.00 —
एसकेएफ बैयरिंग्स	1365.00	1058.00	1270.00	55.00 —
स्पिक	60.25	23.50	46.00	12.00 —
टाटा स्टील	907.50	568.75	851.25	23.75 +
टेल्को	701.00	340.00	670.00	—
वाम आर्गेनिक	103.00	75.00	95.00	6.00 —
विम्को	24.00	11.00	16.75	0.75 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	क्रय मूल्य (रुपए में)	विक्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	11.4427	11.3228
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1267	1.1149
बहरीन	दीनार	1	35.8782	35.8026
बांग्लादेश	टका	100	44.2626	44.2000
कनाडा	डालर	1	11.5604	11.4439
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0884	2.0673
मिस्र	पौंड	1	9.6332	9.5851
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3838	2.3229
हांगकांग	डालर	1	1.7863	1.7684
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0863	0.0800
ईरान	रियाल	100	19.9663	19.9001
इटली	लीरा	100	1.0632	1.0920
जापान	येन	100	11.1235	10.8460
केन्या	शिलिंग	1	0.7732	0.7126
कुवैत	दीनार	1	49.3220	49.2110
मलेशिया	डालर	1	5.4104	5.3498
मारीशस	रुपया	1	1.0432	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6100	0.5900
हालैंड	गिल्डर	1	7.0586	6.9868
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7332	0.7000
सिंगापुर	डालर	1	6.8707	6.7993
स्पेन	पेसो	1	0.1199	0.0998
श्रीलंका	रुपया	1	0.4339	0.4013
स्वीडन	क्रोना	1	2.2855	2.2634
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.5330	9.4344
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1509	0.1399
थाईलैंड	बहत्त	100	54.2990	54.2262
ब्रिटेन	पौंड	1	24.7770	24.0396
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.9373	13.8026
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.6926	3.6215
सोवियत संघ	रूबल	1	17.3232	17.2681
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.0451	7.8431

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 22.6.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दस्तखत के लिए भारत पर दबाव

एकस्व (पेटेंट) के पेरिस समझौते में शामिल होने के लिए भारत पर एक बार फिर दबाव डाला जा रहा है. कुछ वक्त पहले सरकार ने इस पर दस्तखत करने का फैसला लगभग कर लिया था. इसका मतलब है कि भारत पर भी विद्वानों की कृतियों की रक्षा के विश्वव्यापी कानून लागू होंगे. सरकार इस पर दस्तखत करने से इसलिए इनकार करती रही थी क्योंकि उसका ख्याल था कि ऐसा करना देश के हित में नहीं होगा.

लेकिन पिछले साल इस मुद्दे की जांच-पड़ताल के लिए हिंदुस्तान लीवर के अशोक गांगुली, आईईएल के एस. लाहा और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के एस. गांगुली की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई. हालांकि समिति के तीन में से दो सदस्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबद्ध हैं (जो काफी अरसे से भारत से पेरिस समझौते पर दस्तखत करवाने की मुहिम चला रही थीं). लेकिन समिति इस फैसले पर पहुंची है कि पेरिस समझौते पर दस्तखत करने से भारत को कुल मिलाकर कोई फायदा नहीं होगा.

बहरहाल, इस प्रस्ताव पर दस्तखत करने के लिए धड़ेबंदी करने वाले एक शख्स ने इस मामले को एक बार फिर तूल दे दिया है. यह शख्स है पेरिस समझौते के तहत गठित वर्ल्ड इटेलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (डब्लूआईपीओ) के शाहिद अली खां. वे अभी-अभी पदोन्नत होकर डब्लूआईपीओ के सहायक महासचिव बने हैं.

उलटे पांव लौटना पड़ा

लखनऊ की तीसरी बार जिम्मेदारी संभालने से ठीक पहले नारायणदत्त तिवारी 'भारत में पूंजी निवेश के अवसर' विषय पर इंग्लैंड में आयोजित सेमिनार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे. वहां वे अपनी पहल से गए थे.

सेमिनार प्रधानमंत्री की जापान और पश्चिम जर्मनी यात्रा से तुरंत बाद इसलिए आयोजित किया गया था जिससे इस तीसरे देश से भी पूंजी बटोरी जा सके. शुरुआत में माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के तकनीकी सलाहकार सैम पित्रोदा को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना चाहिए. पित्रोदा इस पर राजी भी हो गए थे और सेमिनार के लिए शिकागो से लंदन पहुंचने का उनका कार्यक्रम भी तय हो गया था. तब तिवारी सक्रिय हुए और उन्होंने अनुरोध किया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उन्हें करने दिया जाए. कुछ ब्रिटिश और भारतीयों की अनिच्छा के बावजूद तिवारी लंदन पहुंचे. लेकिन जल्दी ही उन्हें

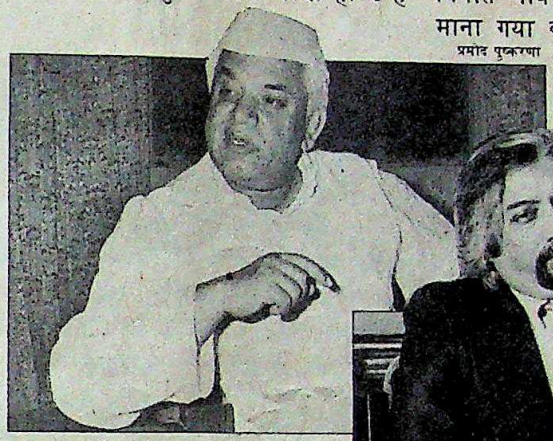

प्रमोद पुष्करणा

तिवारी (बाएं) और पित्रोदा: गए तो सही पर लौटना पड़ा

रजन बसु

लखनऊ की गद्दी संभालने के लिए आखिरकार उलटे पांव वापस लौटना पड़ा.

उत्तराधिकारी की तलाश में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) के अध्यक्ष का पद हथियाने के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई है. यह पद नवंबर में कर्नल एस.पी. वाही के अवकाशप्राप्त करने बाद खाली हो जाएगा. सरकार इस असमंजस में है कि वाही का कार्यकाल या तो बढ़ाए या, उत्तराधिकारी की खोज करे. पर हकीकत में तो उत्तराधिकारी की खोज की प्रक्रिया सार्वजनिक उपक्रम चयन समिति से उम्मीदवारों को छांटने के आदेश के बाद से ही शुरू हो गई है.

भवान सिंह

कर्नल वाही • कार्यकाल बढ़ेगा?

इस महीने के पहले हफ्ते में इस पद के लिए इंटरव्यू देने वालों में सर्वाधिक उल्लेखनीय रहे ओएनजीसी के सदस्य रह चुके अनिल मल्होत्रा जो अब विश्व बैंक में काम कर रहे हैं. दोनों ही एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीएआइएल) के अध्यक्ष विनीत नायर को उपयुक्त इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उनके पास 'बी' श्रेणी अथवा इसके समकक्ष किसी ऐसे संगठन में तीन साल तक अध्यक्षता करने का अनुभव नहीं था.

छाबरिया की कर दी छुट्टी

सरकार द्वारा गठित गैर विवादास्पद समितियों में भी राजनैतिक अखाड़ेबाजी कम नहीं होती. पिछले महीने वित्त और वाणिज्यमंत्री की हैसियत से नारायणदत्त तिवारी ने आप्रवासी भारतीयों की 20 सदस्यीय समिति का गठन किया. इसका भी मामला बहुत कुछ ऐसा ही है. समिति का गठन देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद देने के उद्देश्य से किया गया था.

लेकिन छाबरिया और हिंदुजा बंधुओं की होड़ ने मुसीबत पैदा कर दी. अशोक लेलैंड के मामले में हिंदुजा बंधुओं के हाथों मात खा चुके छाबरिया बंधु समिति की सदस्यता के मसले पर भी उनसे हार गए.

सत्ता केंद्र के करीब पहुंचने की गरज से एम.आर. छाबरिया ने उक्त समिति में शामिल होने के लिए काफी हाथ-पांव मारे. लेकिन आखिरी मौके पर हिंदुजा के एक रिश्तेदार दुबई के रमेश मेंडा ने लंगड़ी मार दी. मेंडा अल हशेर ट्रेडर्स नामक कंपनी चलाते हैं. अबू धाबी के भारतीय दूतावास द्वारा नई दिल्ली को भेजी मूल सूची में छाबरिया का नाम नहीं था. पर इस नामांकन ने बहुतों को नाराज कर दिया है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एएसएलवी

अंतरिक्ष आरोहण को तैयार

पंद्रह महीने की तैयारियों की परीक्षा की घड़ी नजदीक आई

परीक्षा का दिन ज्यों-ज्यों निकट आ रहा है, त्यों-त्यों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के इतिहास की सबसे रोमांचक घड़ियां भी निकट आती जा रही हैं. पिछले 15 महीने से तिरुअनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तथा श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिक दिन-रात एक किए हुए हैं. आने वाले पखवाड़े में आंध्र प्रदेश के पूर्वी समुद्र में स्थित टापू शार से 40 टन वजन वाले ऑग्मेंटेड सैटेलाइट लांच वेहिकल (एएस-एलवी) यानी संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण किया जाना है. इस प्रक्षेपण की सफलता या असफलता से यह तय हो जाएगा कि भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा या नहीं?

पिछले पखवाड़े प्रक्षेपण की तैयारियां तब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गईं जब तिरुअनंतपुरम के 40 हजार एकड़ क्षेत्रफल वाले शार केंद्र के निदेशक एम.आर. कुरुप की अध्यक्षता में प्रक्षेपण अनुमति बोर्ड की बैठक हुई और पूर्व निर्धारित 25 जून के स्थान पर प्रक्षेपण की तिथि को जून के पहले पखवाड़े के लिए तय कर दिया गया. वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों ने 40 मीटर ऊंचे मोबाइल सर्विस टावर की सहायता से 23.5 मीटर ऊंचे रॉकेट के एक-एक खंड को जोड़कर रॉकेट को टावर में खड़ा कर दिया. उसके बाद 150 किलो वजन वाले रोहिणी उपग्रह को यान के साथ जोड़ दिया गया. यह यान इस उपग्रह को 450 किलोमीटर ऊंची लगभग गोलाकार कक्षा में स्थापित कर देगा.

प्रक्षेपण से 10 दिन पहले यान की अंतिम जांच और उपग्रह की सही हालत जानने के लिए वैज्ञानिकों को 84 पृष्ठों वाले काउट-डाउन मैनुअल पर निर्भर रहना होगा. यह कार्रवाई 900 टन इस्पात से बने मोबाइल सर्विस टावर की तंग सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर तथा वहां से प्राप्त आंकड़ों की प्रक्षेपण स्थल से 100 मीटर दूर कंकरीट से बने ब्लॉक हाउस में लगे कंप्यूटरों और 6 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित मिशन कंट्रोल केंद्र में जांच-परख की जाएगी.

उस समय ब्लॉक हाउस और मिशन कंट्रोल से मिलने वाले कंप्यूटर संकेतों के आधार पर शार तथा कार निकोबार में तैनात वैज्ञानिक उन रडार स्टेशनों को सक्रिय कर देंगे जिनकी मदद से अंतरिक्ष यान की प्रगति का अध्ययन किया जाएगा. इसके अलावा हैदराबाद के निकट शादनगर और पश्चिमी जर्मनी के वाइलहाइम में उपग्रह पर नजर रखने वाले केंद्र भी अपना काम शुरू कर देंगे. कक्षा में पहुंचने पर रोहिणी उपग्रह इन केंद्रों को संकेत और आंकड़े भेजेगा जिन्हें ये केंद्र ग्रहण कर लेंगे. अभियान के निदेशक एम.एस. रघुचंद्रन देव चुटकी लेते हुए कहते हैं, "इस मौके पर हमें ऐसा लगता है कि मानो हम स्कूली बच्चे हैं जो वार्षिक परीक्षा में बैठे हुए हैं. मात्र 460 सेकेंड में ही एएसएलवी की उड़ान से हमारी वर्षों की मेहनत की परीक्षा हो जाएगी."

देव की यह चुटकी वैज्ञानिकों के उस उत्साह की झलक देती है जो पिछले साल 24 मार्च के दिन एएसएलवी उड़ान की असफलता के कारण आए सदमे और उलझन के बाद फिर से पैदा हुआ है. दूसरी उड़ान की तैयारी में वैज्ञानिकों को उस 12 महीने की अवधि से अधिक समय लगा है जो कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रो. यू.आर. राव ने तय की थी. दूसरी उड़ान की तैयारी में उन बातों और निष्कर्षों का पूरा ध्यान रखा गया है जो असफल उड़ान से मिले आंकड़ों, असफलता की जांच के लिए बनाई गई समिति (एफएसी) तथा आपसी बातचीत से सामने आए हैं. विक्रम साराभाई केंद्र के सहायक निदेशक आर. अरवामुदन की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने ज्वलन प्रणाली और प्रथम चरण मोटर में आई खराबियों के बारे में सभी संभावित कारणों की व्याख्या की है. प्रो. राव कहते हैं कि इसके आधार पर अब पूरी ज्वलन प्रणाली को बदल दिया गया है.

एएसएलवी का निर्माण पहली पीढ़ी के एसएलवी किस्म के रॉकेटों के अनुभव किया गया है और इसमें बाद दिए जाने वाले दो बूस्टर भी लगाए गए हैं जो एसएलवी की प्रथम चरण मोटर से लिए गए हैं. लेकिन इस सबके बावजूद पांच चरणों वाला यह रॉकेट अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले एक बेहतर तकनीकी प्रगति का नमूना है. एसएलवी रॉकेट केवल 35 किलोग्राम

"कुछ प्रयोगों को छोड़ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. हमें कुछ सोचा-समझा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा."

यू.आर. राव
अध्यक्ष, 'इसरो'

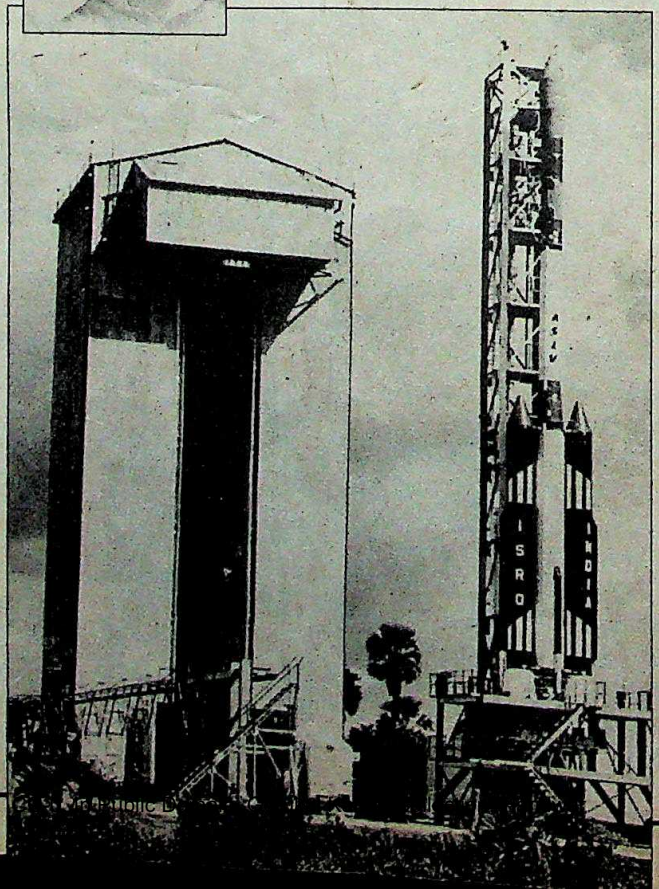

यू.आर. राव; और (नीचे) शार में मोबाइल सर्विस टावर

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के उपग्रह ले जा सकता है जबकि एएसएलवी की क्षमता 150 किलो है. इसके अलावा रॉकेट की दिशा और गति को ठीक करने की भी व्यवस्था की गई है.

पिछले साल के असफल अभियान के बाद जो एक बड़ा परिवर्तन किया गया है वह प्रक्षेपण मंच के डिजाइन में है. आग से बचाव के लिए नई कवच व्यवस्था के अलावा ब्लॉक हाउस में भेजे जाने वाले आंकड़ों की प्रेषण व्यवस्था में बदलाव किया गया है और मिशन कंट्रोल केंद्र में लगे पुराने आइरिस-55 कंप्यूटर के अलावा वीएएक्स 11-750 किस्म के नए कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है.

हालांकि एएसएलवी अभियान का मुख्य लक्ष्य नई किस्म के रॉकेटों की उड़ान क्षमताओं की परख करना है लेकिन इस यान द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाने वाले 150 किलो वजनी रोहिणी उपग्रह से कम खर्च में अंतरिक्ष से अध्ययन की सुविधाएं भी मिल सकेंगी. इस उपग्रह में भारत-जर्मन सहयोग से विकसित मोनोक्यूलर इलेक्ट्रो ऑप्टिक स्टीरियो स्कैनर (मिओस) कैमरे को लगाकर उसकी उपयोगिता की जांच की जाएगी. एक अन्य प्रयोग के तहत सूर्य में होने वाले गामा किरण विस्फोटों का अध्ययन किया जाएगा जिससे गामा किरणों के स्रोतों की सही जानकारी मिल सके.

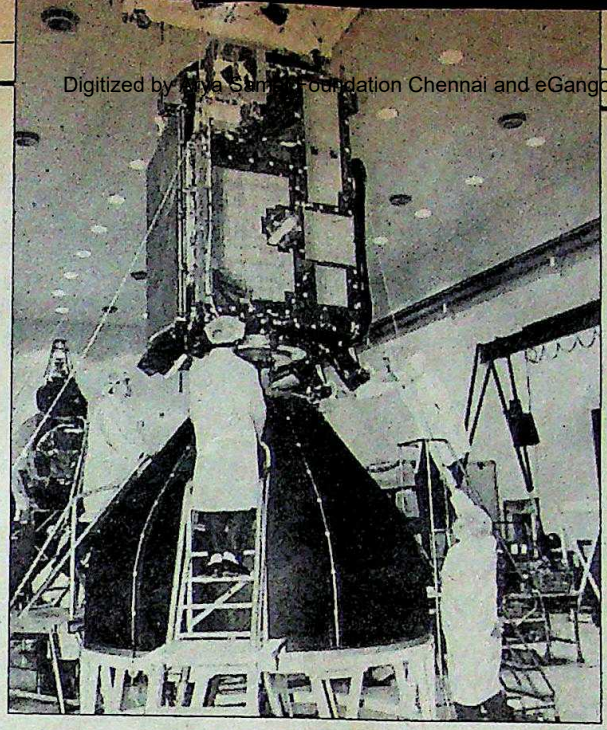

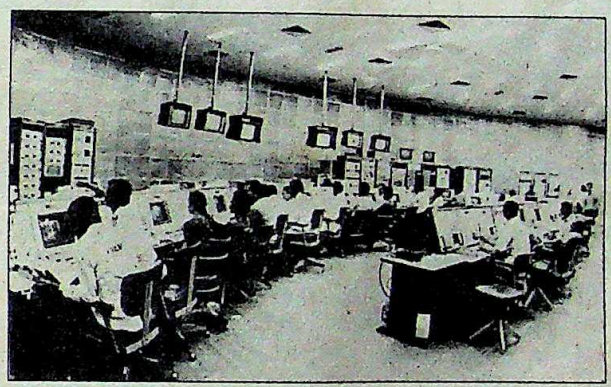

इंसैट-1 सी (ऊपर) का परीक्षण; और शार में एएसएलवी का ब्लॉक हाउस

हालांकि पिछले साल रोहिणी उपग्रह में गामा किरणों के अध्ययन के लिए अपेक्षाकृत बड़े प्रयोग की व्यवस्था थी और भूमि से उपग्रह के आवर्तकों पर लेसर किरणें फेंककर उसकी ऊंचाई मापने के प्रयोग का प्रावधान रखा गया था लेकिन इस बार प्रो. राव कहते हैं, "अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि कुछ प्रयोगों को छोड़ दिया जाए और जरूरी हो तो उन्हें बाद में कभी किया जाए. हमें कुछ सोचा-समझा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा. जब हमने यूरोप से संचार उपग्रह 'एपल'—एरियान पैसेंजर पेन्लोड एक्सपेरिमेंट—का प्रक्षेपण किया था तब भी हमें एरियन प्रक्षेपास्त्रों की असफलता की पूरी-पूरी जानकारी थी."

भविष्य में भेजे जाने वाले अधिकांश दूरसंवेदी उपग्रहों का मुख्य लक्ष्य भारत के स्थल आकृति संबंधी सटीक नक्शे तैयार करना होगा. इसके लिए बहुत बारीकी से विवरण देने वाले उपग्रह चित्रों का होना जरूरी है. अब तक यह महत्वपूर्ण बात छूटी रही है कि क्षेत्रीय उठान की सही जानकारी प्राप्त हो. उपग्रह के स्कैनर से प्राप्त होने वाले आंकड़े हैदराबाद की राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी (एनआरएसए) के शादनगर ट्रेकिंग सेंटर के माध्यम से ऊंचे घनत्व वाले कंप्यूटर टेपों पर रिकार्ड करके अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में भेजी जाएंगी. वहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी चित्र तैयार करके ये चित्र विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे. मौसम विभाग इन चित्रों का उपयोग बादलों की ऊंचाई जानने के लिए और भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग जमीन में छिपे खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए करेगा. इन चित्रों से तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को प्राणहिता-गोदावरी घाटी में तेल भंडारों को खोजने में मदद मिलेगी और गांगेय क्षेत्र में बाढ़ वाले स्थानों का भी पता लगाया जा सकेगा.

वर्तमान योजना के तहत 18 महीनों के अंतर पर दो और एएसएलवी उपग्रह छोड़े जाएंगे जिनमें वायुगति विज्ञान, एक्सरे, खगोलशास्त्र और भूगणितशास्त्र संबंधी प्रयोग किए जाएंगे. 26 करोड़ रुपए की लागत वाले एएसएलवी कार्यक्रम के बाद 350 करोड़ रुपए की लागत वाला पोलर सैटेलाइट लांच वेहिकल प्रोग्राम हाथ में लिया जाएगा. इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1000 किलोग्राम से भारी दूरसंवेदी उपग्रहों के सूर्य के समतुल्य पृथ्वी कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा जहां से ये उपग्रह सूर्य की रोशनी वाले पृथ्वी क्षेत्रों का अध्ययन कर सकेंगे. लेकिन एएसएलवी से पीएसएलवी तक की यह छलांग कोई छोटी बात नहीं है. पीएसएलवी में चार चरणों वाला रॉकेट होगा जिनमें बारी-बारी से ठोस और तरल ईंधनों का उपयोग किया जाएगा. दरअसल तीसरी पीढ़ी के रॉकेटों में ठोस ईंधन वाले चरणों का अध्ययन करने के लिए श्रीहरिकोटा में एक गुफाकार ऊंचा भवन भी तैयार हो चुका है. हालांकि इसरो की योजना पहला पीएसएलवी रॉकेट 1989 में छोड़ने की है पर वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि जिस गति से काम हो रहा है उसे देखते हुए 1992 से पहले इसकी उम्मीद करना सिर्फ बेमानी ही होगा.

इन रॉकेटों के विकास के लिए की गई अथाह मेहनत के बारे में कुरुप का कहना है, "पिछले साल की असफलता के बावजूद दोबारा प्रयास करने के फैसले से हमारे लोगों में जो उत्साह आया वह अभूतपूर्व है. सभी शुबहों को दूर कर दिया गया है और जरूरी परिवर्तन भी कर दिए गए हैं." साराभाई केंद्र के एक युवा इंजीनियर की टिप्पणी थी, "पिछले साल की असफलता के बाद प्रक्षेपण से पहले की उत्तेजना ने उलटा असर दिखाया. रॉकेट की असफलता के मुकाबले इसने हमारे मनोबल को ज्यादा नुकसान पहुंचाया. इसलिए इस बार हम लोग चुपचाप काम में लगे हुए हैं." मिशन के निदेशक देव भी यह मानते हैं कि प्रक्षेपण से पहले और असफलता के बाद के जोरदार प्रचार ने हम में से लगभग हर व्यक्ति को प्रभावित किया, पर इस बार की बात ऐसी है कि कोई भी वैज्ञानिक अपनी उत्सुकता को छिपा नहीं पा रहा है.

—अमरनाथ के. मेनन, त्रिवेंद्रम और श्रीहरिकोटा में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूकंप का भूत

बाढ़, सूखा, महामारी और भूकंप जैसी तमाम प्राकृतिक विपदाओं में सबसे भयानक माना जाता है भूकंप को. यों तो प्राकृतिक विपदाएं कभी भी, कहीं भी कहर ढा सकती हैं और कुछ की भविष्यवाणी बहुत हद तक संभव भी है. लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी भूकंप विज्ञानियों के लिए हमेशा से चुनौती रही है. पिछले महीने 7,8 और 10 जून को पृथ्वी का यह कंपन केरल के इदुक्की पनबिजली संयंत्र के पास दर्ज किया गया. भूकंप से 500 घरों की दीवारों और एक अस्पताल की छत में दरार पड़ गई, पर कोई भी इमारत ढही नहीं. पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. उसके बाद 21 और 22 जून को इदुक्की पनबिजली संयंत्र के पास फिर भूकंप के झटके आए.

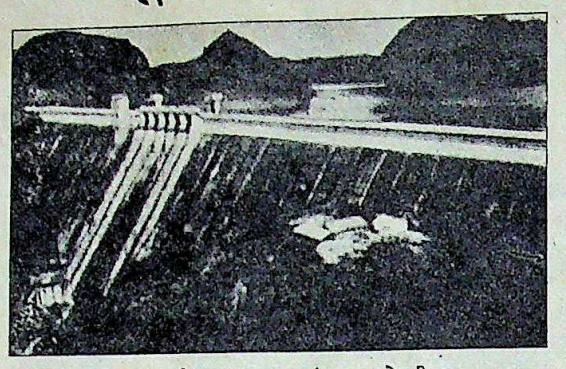

इदुक्की जलाशय: भूकंप का स्रोत?

इन घटनाओं ने राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और तिरुअंनतपुरम के भूविज्ञान अध्ययन केंद्र के विज्ञानियों का ध्यान खींचा, क्योंकि कुछ भूकंप विज्ञानी यह मानते हैं कि बांध के पीछे जलाशय भर देने से भूचाल आता है. जाने-माने भूकंप विज्ञानी और कोचीन के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. हर्ष गुप्ता के मुताबिक जलाशयों की वजह से भूकंप के अब तक 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

पर सारे भूकंप विज्ञानी बांध और भूकंप के इस रिश्ते को नहीं मानते. इदुक्की जलाशय में लगातार पानी डाला जाता रहा है लेकिन जब इसमें अब के मुकाबले कहीं ज्यादा पानी था तब कोई गड़बड़ नहीं हुई. गुप्ता बताते हैं कि बांध की वजह से आए भूकंप के मामले में झटकों का सिलसिला शुरू हो जाता है, "अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि 7 जून का भूकंप इदुक्की जलाशय के कारण आया था."

समय की बचत

बंगलूर की राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (रावैप्र) जब विमानों के डिजाइन विकसित करने में समय की बचत का तरीका खोजने लगी तो उसे अपने ही गिरेबां में झांकना पड़ा. 'रावैप्र' के विज्ञानियों ने पता लगाया कि जिस समस्या के लिए वे कंप्यूटर पर 20 घंटे तक सिर खपाते हैं उसे एक 'पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर' से बहुत तेजी से हल किया जा सकता है. अब वे दो साल में ही देश का ऐसा पहला कंप्यूटर बना लेंगे. इसका नाम होगा 'प्लोसॉल्वर' और इसकी लागत बैठेगी 5 लाख रुपए. इस कंप्यूटर की काम करने की गति 'रावैप्र' के मौजूदा 'मेनफ्रेम कंप्यूटर' से दुगनी होगी और खर्च 50 गुना कम बैठेगा. परंपरागत कंप्यूटर किसी समस्या का हल कदम-दर-कदम निकालते हैं, जबकि पैरेलल कंप्यूटर इसे कई टुकड़ों में बांट देता है और एक साथ ही सारे हल निकाल लेता है.

'रावैप्र' अब अपने पैरेलल कंप्यूटर की गति को 6 लाख ऑपरेशन प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 20 लाख ऑपरेशन प्रति सेकेंड करने की योजना बना रही है. यह गति भारत में उपलब्ध किसी भी मेनफ्रेम कंप्यूटर से 20 गुना ज्यादा है. 'रावैप्र' के निदेशक डॉ. आर. नरसिंहम कहते हैं, "विशिष्ट कार्यों के लिए भारत में ऐसा पैरेलल कंप्यूटर बनाना मुमकिन है जो मौजूदा मेनफ्रेम कंप्यूटरों से सस्ता और काम में काफी तेज हो."

रफ्तार का रिकार्ड

सात वातानुकूलित कुर्सीयानों (कुल 470 सीट) वाली 'शताब्दी एक्सप्रेस' 10 जुलाई को जब नई दिल्ली से 411 किलोमीटर दूर झांसी की अपनी मंजिल के लिए रवाना होगी तो भारतीय रेल अपनी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार वाली सीमा पार कर जाएगी. शताब्दी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. इसकी यह रफ्तार 3,900 हॉर्स पावर के विकसित डब्लूएपी-3 इंजन से ही मुमकिन हो सकी है. इसे लखनऊ के शोध, खाका व मानक संगठन ने तैयार किया है.

इसके लिए 3,900 हॉर्स पावर के मौजूदा इंजन में कुछ सुधार किए गए . झटकों को सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें उम्दा रबर के पुर्जे लगाए गए, ब्रेक में सुधार किया गया. इससे इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ गई. लेकिन इसमें यह व्यवस्था भी है कि अगर इसकी रफ्तार 145 किमी प्रति घंटा से ज्यादा बढ़े तो इसमें अपने आप ब्रेक लग जाए. साथ ही इसमें यह इंतजाम भी किया गया है कि अगर ड्राइवर रुकने के सिगनल की अनदेखी कर जाए तो ट्रेन चार सेकेंड में अपने आप रुक जाए.

शताब्दी एक्सप्रेस: सबसे तेज

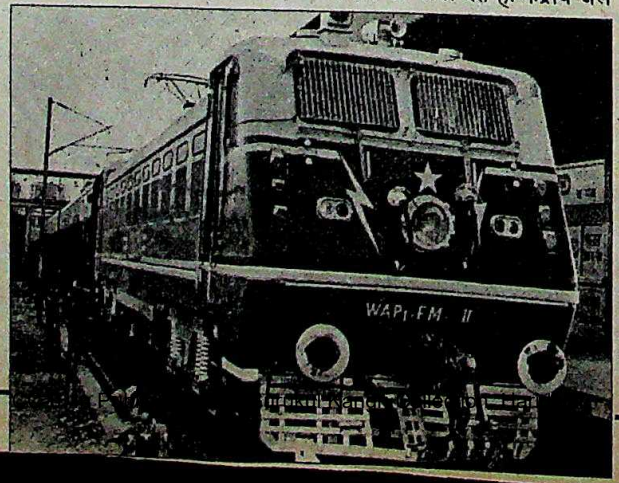

बर्फ पिघलेगी

उत्तर भारत की पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए हिमालय के हिमनदों (ग्लेशियर) को पिघलाने की योजना की भारी आलोचना हो रही है. ये हिमनद हिमालय से निकलने वाली 22 नदियों को पानी देते हैं. केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष एम.ए. चिताले के अनुसार कंप्यूटरों की मदद से हवाई सर्वेक्षण किया गया है. सर्वेक्षण में पाया गया कि जब व्यास नदी के जलग्रहण क्षेत्र के छोटे-से इलाके पर हेलीकॉप्टर से चारकोल की गर्द छिड़की गई तो बर्फ पिघलने लगी. पर योजना का विरोध करने वालों ने बहुत से तर्क दिए हैं.

उनके मुताबिक पहली बात तो यह है कि योजना काफी खर्चीली है. मनाली के 'हिम व हिमस्खलन अध्ययन संस्थान' (एसएएसई) ने अंदाज लगाया है कि बर्फ पिघलाकर एक किलो लीटर पानी बनाने पर 3 रुपए का खर्च बैठेगा, जबकि परंपरागत तरीके से भूमिगत जल को खींचने पर यह खर्च एक रुपए से भी कम बैठता है.

वैसे चारकोल की गर्द बरसाना अपनेआप में एक भारी-भरकम काम है. इसके लिए 30 वर्ग किलोमीटर के हिमनद पर कार्बन का 188,000 टन से भी ज्यादा बारीक बुरादा बरसाना होगा, तब जाकर कहीं इस पर कार्बन के बुरादे की 0.1 मिलीमीटर की परत बिछ सकेगी. कृत्रिम ढंग से हिमनद पिघलाने से पर्यावरण को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसका असर इसके निचले इलाकों के जंगल पर पड़ेगा. बहरहाल, विज्ञान व तकनीक विभाग हिमनदों को पिघलाने की योजना का अध्ययन कर रहा है. पर लगता है कि आखिर में जीत हिमनद विज्ञानियों की ही होगी.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वायुसेना

एक और अप्रिय मिसाल

वरिष्ठता क्रम तोड़कर मेहरा वायुसेनाध्यक्ष नियुक्त

इस साल फरवरी-मार्च में भारतीय वायु सेना ने अपनी आक्रमण पंक्तियों की क्षमता परखने के लिए एक बड़ा सैनिक अभ्यास ऑपरेशन हैमर ब्लो किया. इस अभ्यास में पश्चिमी वायुकमान और दक्षिण-पश्चिमी वायुकमान के बीच होड़ थी.

यह होड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि इन दोनों कमानों के अगुआ अधिकारियों — पश्चिमी कमान के एअर मार्शल एम.एम. सिंह और दक्षिण-पश्चिमी कमान के एअर मार्शल एस.के. (पॉली) मेहरा—के बीच वायुसेना का शीर्ष पद पाने की प्रतिस्पर्द्धा चल रही थी. पश्चिमी कमान ने अभ्यास के दौरान दक्षिण-पश्चिमी कमान को पछाड़ तो दिया पर तीन ही महीने बाद एम.एम. सिंह पद की दौड़ में पिछड़ गए. वे वायुसेना के सबसे वरिष्ठ एअर मार्शल हैं और वायुसेनाध्यक्ष डेनियल ला फांतेन के बाद उन्हीं का नंबर था. पर 20 जून को उनकी वरिष्ठता लांघकर मेहरा को अगला वायुसेनाध्यक्ष बना दिया गया.

जब रक्षा मंत्रालय ने मेहरा की नियुक्ति की घोषणा की उस वक्त एम.एम. सिंह कश्मीर गए हुए थे. 23 जून को दिल्ली लौटने पर उन्होंने 31 जुलाई से समय पूर्व अवकाशग्रहण करने के लिए आवेदन कर दिया क्योंकि इसके अगले ही दिन मेहरा कार्यभार संभालने वाले हैं. वरिष्ठता लांघने की इस घटना से वायु भवन के गलियारों में निराशा की लहर दौड़ गई.

सरकारी प्रवक्ता गोपी अरोड़ा का कहना था, "वरिष्ठता लांघना कोई नई बात नहीं है. 1973 में ही एअर मार्शल इंजीनियर को फलांगकर ओ.पी. मेहरा वायुसेनाध्यक्ष बनाए गए थे." फिर भी वरिष्ठता की अनदेखी कभीकभार ही की गई है. इसके दो ही उदाहरण हैं. 1973 में एअर मार्शल इंजीनियर का और 1984 में लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा का.

सैन्य कार्रवाई के हिसाब से एम.एम. सिंह का रिकार्ड मेहरा से कहीं ज्यादा अच्छा रहा है. पश्चिमी वायुकमान वायुसेना का महत्वपूर्ण अंग है और इसका कार्यक्षेत्र पाकिस्तानी वायुसेना जितना ही बड़ा है. भारतीय वायुसेना में जो 39 लड़ाकू

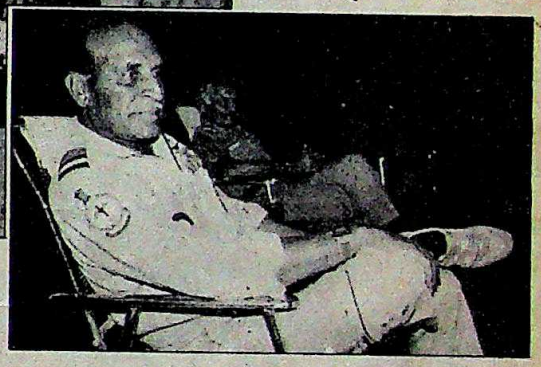

उड़ने की तैयारी में सिंह (ऊपर), और मेहरा (दाएं): विवादास्पद नियुक्ति

स्क्वाड्रन हैं उनमें 25 तो इसी कमान के तहत आते हैं. रक्षा मंत्रालय ने ला फांतेन से इन दोनों अधिकारियों के कामकाज के बारे में लिखित विवरण मांगा था. बताया जाता है कि ला फांतेन ने जवाब भेजा कि सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर एम.एम. सिंह का शानदार रिकार्ड रहा है जबकि वर्षों वायुसेना मुख्यालय में रहने के कारण मेहरा की प्रशासनिक समझ बहुत अच्छी है.

मेहरा को वायुसेना प्रमुख बनाने का कई महीने से आधार तैयार किया जा रहा था. ला फांतेन ने कई महीने पहले रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत के हवाले से एम.एम. सिंह को सूचित किया था कि मेहरा अगले वायुसेना प्रमुख होंगे. ला फांतेन ने पंत का यह अनुरोध भी उन तक पहुंचाया कि वे मेहरा की नियुक्ति की घोषणा से पहले इस्तीफा दे दें. लेकिन एम.एम. सिंह ने इनकार कर दिया. फिर 26 मई को रक्षा सचिव एस.के. भटनागर ने अपने रिटायर होने के पांच दिन पहले उन्हें बुलाया और कहा कि खुद को और सरकार को उलझन से बचाने के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. पर एम.एम. सिंह ने फिर इनकार कर दिया.

रक्षा मंत्रालय ने एम.एम. सिंह के साथ हुई इन बैठकों के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है, हालांकि 'इंडिया टुडे' ने उसे इस विषय पर लिखित सवालात दिए थे. उधर भटनागर ने भी इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी एम.एम. सिंह से इस्तीफा देने के लिए कहा था. इस बीच, मेहरा की नियुक्ति के साथ-साथ अखबारों में इस आशय की मनगढ़ंत खबरें छपनी शुरू हो गईं कि एम.एम. सिंह अपने अशांत पारिवारिक जीवन और एक प्रेम-प्रसंग के कारण वायुसेना प्रमुख बनने से वंचित रह गए. वायु भवन के आला अफसरों ने इस तरह की खबरों पर आपत्ति करते हुए कहा कि वरिष्ठतम एअर मार्शल की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला जा रहा है. अरोड़ा ने इस बात से इनकार किया कि एम.एम. सिंह को उनके निजी जीवन के कारण वायु प्रमुख नहीं बनाया गया.

लेकिन खुफिया ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार एम.एम. सिंह की 'महिला मित्र' के बारे में हैदराबाद में और उनकी राजनैतिक आस्था के बारे में चंडीगढ़ में जांच की गई थी. सरकार एम.एम. सिंह को कोई दूसरा काम देने की पेशकश भी करती रही जिसे वे ठुकराते रहे. उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों से कहा, "सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण है," पर सेना के मामले में उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एम.एम. सिंह की वरिष्ठता लांघने के फैसले से सरकार ने एक बार फिर अप्रिय मिसाल कायम की है और इसके एवज में एक महत्वपूर्ण अधिकारी की सेवाएं खो दीं.

—रमिंदर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'कशमकश' से 'उड़ान' तक: लगातार ४८ घंटे का कड़ा परीक्षण दौर.

हर पिरामिड टी वी को गुजरना होता है लगातार ४८ घंटे चलते रहने की कड़ी अग्नि परीक्षा से.

इस तरह की अग्नि परीक्षा के कुछ अपने फ़ायदे है.

सेट में किसी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी हो तो वह छुप नहीं सकती और उस को तुरंत दुरुस्त किया जा सकता है. इस प्रकार यह पक्का हो जाता है कि पिरामिड का कोई भी दोषपूर्ण सेट बाज़ार मे आ ही नहीं सकता.

ज़्यादातर टी वी इस तरह का परीक्षण तो करते है पर सिर्फ़ ६ घंटे तक. कुछ एक १२ घंटे तक. और कुछ २४ घंटे... लेकिन इससे अधिक नहीं.

वेव सॉल्डरिंग : भारत के १०० से भी अधिक टी वी जो नहीं करते.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों के लिए वेव सॉल्डरिंग बिल्कुल वैसी ही ज़रूरी चीज़ है जैसी कि कपड़ों के लिए सिलाई : यानी हर जोड़ पूरे एहतियात और मज़बूती के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए.

बदक़िस्मती से भारत के अधिकांश टी वी में आज भी सॉल्डरिंग हाथों से की जाती है. एक ऐसा घटिया तरीक़ा जो टी वी की परिपूर्णता में सबसे बड़ी रुकावट है.

कुछ गिने-चुने ब्राण्डो में केवल पिरामिड ही ऐसा एकमात्र टी वी है किजसमें इस्तेमाल की जाती है वेव सॉल्डरिंग– पूरी तरह अचूक एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया जो दिलाती है सौ-फ़ीसदी बेहतरीन कामगिरी.

बिल्कुल वही फ़र्क, जो मशीन की सिलाई और हाथ से की जानेवाली कच्ची सिलाई के बीच होता है.

टी वी की सर्विस होनी चाहिए तब, जब यह काम कर रहा हो पूरी कुशलता से.

इसे हम कहते है प्रीवेंटिव मेन्टेनेन्स यानी ख़राबी की रोकथाम करने वाली देखभाल. जिसे हम हर पिरामिड टी वी के लिए बिल्कुल मुफ़्त करते है.

पहले वर्ष के दौरान, हर तीन महीने में हमारा इंजीनियर आपके पास आएगा.

वह आपके एन्टीना को ठीक-ठीक करेगा, आपके सेट की सफ़ाई करेगा, और पूरी तरह इसकी जांच-पड़ताल करेगा. यदि कोई छोटी-मोटी ख़राबी होगी, तो उसी वक़्त ठीक कर देगा.

ये तो हमारी सेवाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है.

आपका पिरामिड टी वी घर पहुंचने के दो हफ़्ते बाद ही कंपनी का इंजीनियर आपके घर पहुंचकर देखेगा कि आपका सेट सही तरीके से लगाया गया है या नहीं? और यह बढ़िया ढंग से काम कर रहा है या नहीं?

और इसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो फ़ोन कीजिए, हमारा इंजीनियर २४ घंटे या इससे भी कम वक़्त में आपकी सेवा में मौजूद होगा!

बदक़िस्मती से कभी आपका सेट मरम्मत के लिए सर्विस सेन्टर ले जाना पड़े तो बदले में हम आपको दूसरा सेट देंगे. यानी आपको अपना मनपसंद कार्यक्रम 'चित्रहार' देखने के लिए पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी!

दरअसल गारंटी है किसकी सुरक्षा : आपकी या निर्माता की?

आज, ज़्यादातर गारंटिया देखकर आप सोचते होंगे कि आख़िर इसका मतलब क्या है?

इनमें लंबी-चौड़ी सूची तो उन नामों की होती है जिनकी गारंटी नहीं दी जाती.

और जिस सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में निर्माता जान-बूझकर ख़ामोश रहते है : वह है पिक्चर ट्यूब.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड की गारंटी इसके खरीदारों को ध्यान में रखकर दी जाती है.

बग़ैर किसी संशय के, पूरी तरह बेनुक्स गारंटी. जिसमें पिक्चर ट्यूब भी शामिल होती है.

ऐसी गारंटी जो आपको सुरक्षा देती है... न कि निर्माता को.

पिरामिड में एक खासियत नहीं जो ज़्यादातर दूसरे टी वी में होती है : धूल-गर्द.

धूल-गर्द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की सबसे ख़तरनाक दुश्मन है.

बदक़िस्मती से ज़्यादातर टी वी जब कारखाने से निकलते है तो इनमें धूल या गर्द मौजूद होती है.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड कारखाने में तकनीकी साफ़-सफ़ाई के सबसे ऊंचे स्तर को कायम रखा जाता है. तभी तो हर पिरामिड टी वी तैयार होता है पूरे धूल नियंत्रित वातावरण में.

पिरामिड : न कोई चिंता, न कोई ग़म इस टी वी में ऐसा दम.

टी वी ख़रीदते समय आपका पहला सवाल यही होता है– "इसके निर्माता कौन है?"

और हमारे पास है इसका बहुत ही ठोस और विश्वसनीय जवाब. क्योंकि पिरामिड के निर्माण के पीछे है ६०० करोड़ रुपये की बिक्री का– लालभाई ग्रुप.

बरसों की मेहनत और लगन के बलबूते पर लालभाई ग्रुप ने टेक्सटाइल्स, एअरकंडीशन से, केमिकल्स, इंजीनियरिंग और फ़ायनान्स के क्षेत्र में ऊंचे दर्जे के उत्पादन तैयार करके अपनी ख़ास पहचान बनाई है.

इसीलिए तो जब आप पिरामिड खरीदते है तो आपको किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती.

क्योंकि आपकी तमाम फ़िक्रों का बोझ पहले ही उठा लिया है लालभाई ग्रुप ने.

पिरामिड पेश करते है पिरामिड २००० ई, पिरामिड २००० आर, पिरामिड प्लस (रिमोट और नॉन रिमोट), पिरामिड परफ़ेक्ट और पिरामिड २०९ जे कलर में. पिरामिड १४२, पिरामिड १४५ टी और पिरामिड १४५ ई, ३६ cms ब्लैक एण्ड व्हाईट पोर्टेबुल में, पिरामिड ५१०और पिरामिड ५११ ५१ cms ब्लैक एण्ड व्हाईट में.

पिरामिड . . . इसमें कोई शक नहीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Regd. Office: Arvind Mills Ltd. (E.D.), Naroda Road, Ahmedabad. Ph: 378165 • 8 Community Centre, Saket, New Delhi. Ph: 663816. • 8th Floor, Shah House, Worli, Bombay. Ph: 4939274 • IInd Cross Street, West C.I.T. Nagar, Madras. Ph: 451621. • C A, 49, Sector-1, Salt Lake City, Calcutta

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

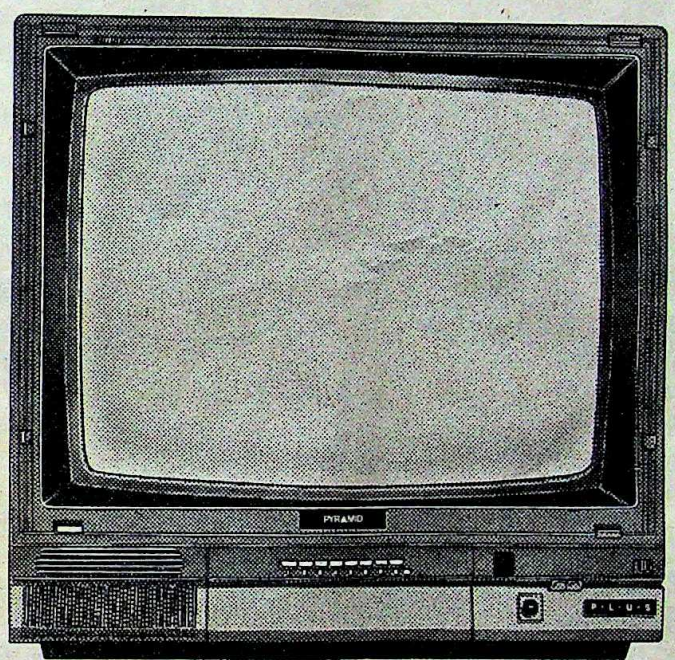

PYRAMID

COLOUR TELEVISION

THE LALBHAI GROUP

जापानी टेक्नालॉजी का उत्पादन.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Trikaya.AMED.12.88.HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नौसेना

कैप्टन पर संदेह

दस्तावेजों की तस्करी के आरोप

बंबई पुलिस और खुफिया ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के अवकाशप्राप्त अधिकारी कैप्टन बुद्धिकोटा सुब्बाराव को सुरक्षा से संबंधित कुछ नाजुक दस्तावेज देश से बाहर ले जाने के प्रयास के आरोप में क्या गलत सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था? यह सवाल 30 मई को सहार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर न्यूयॉर्क के लिए एअर इंडिया की उड़ान पकड़ने से पहले 47 वर्षीय इस पूर्व नौसेना अधिकारी की सनसनीखेज गिरफ्तारी के बाद पैदा हुआ है.

सुब्बाराव सीएट कंपनी के एक विशेष कार्य से अमेरिका जा रहे थे. उन्होंने हाल ही में कंपनी के परामर्शदाता का काम शुरू किया है. सिएट वालों का कहना है कि कैप्टन तीन महीने के एक परामर्श करार के तहत अमेरिका में बाजार सर्वेक्षण करने वाले थे और उनके "काम का क्षेत्र न तो गोपनीय है और न ही कंप्यूटरों से संबंधित, जैसा कि अखबारों में लिखा गया है."

सिएट को दी जा रही सेवाओं से संबंधित कागजात के अलावा सुब्बाराव के पास कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ किए पत्र-व्यवहार की फाइल भी मिली. साथ ही हाल में 12वीं कक्षा पास कर चुके उनके बेटे के स्कूल सर्टिफिकेट भी उनसे बरामद हुए. लगता है कि उनकी अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में खुद अपने और अपने बेटे के दाखिले की संभावनाओं का पता लगाने की योजना थी. आंध्र विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पा चुके सुब्बाराव ने 1985 में बंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से 'परमाणु रिएक्टर के ढांचे में खामियों का गणितीय विश्लेषण' विषय में पीएचडी भी की.

लेकिन इस गिरफ्तारी ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उनके जाने का सुराग पाकर खुफिया विभाग के गुप्तचरों और बंबई पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली. कुछ कागजात पर 'अति गोपनीय' शब्द लिखे देखकर पुलिस के कान खड़े हो गए. हवाई अड्डे पर धरे जाने के बाद शहर में उनके फ्लैट की तलाशी से भी कुछ और दस्तावेज मिले. हवाई अड्डे पर जब्त किए दस्तावेजों में नौसेना के इस पूर्व इंजीनियर के वे कागजात भी शामिल थे जो उन्होंने पनडुब्बियों के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की एक परियोजना के तहत काम करते वक्त तैयार किए थे. अब बंद हो चुकी यह परियोजना '70 के दशक में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने भारतीय नौसेना के सहयोग से शुरू की थी.

पदमुक्त होने के कुछ ही पहले सुब्बाराव ने भाभा केंद्र द्वारा तैयार किए पहले दो नमूनों की समालोचना नौसेना के उच्चाधिकारियों के सामने पेश करने का दावा किया जिसमें परमाणु संयंत्र के नमूनों की खामियों

प्रतिभा के धनी सुब्बाराव को विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारतीय नौसेना दो बार सम्मानित कर चुकी है

का खुलासा किया गया था. इसके बाद सुब्बाराव ने 90 मेगावाट और 40 मेगावाट के परमाणु नोदक संयंत्र के खुद तैयार किए नमूने प्रस्तुत किए. उनका मानना था कि उनके नमूने भाभा केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए नमूनों से बेहतर हैं. लेकिन उनकी ये दलीलें वैज्ञानिकों को लुभा नहीं पाईं. इससे इन अटकलों को बल मिलता है कि उनकी गिरफ्तारी में उनके किसी पूर्व सहयोगी का ही हाथ है.

भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी का एक और नमूना तैयार करने के लिए कुछ वर्ष पहले जब उन्नत तकनीक पोत कार्यक्रम शुरू किया तो सुब्बाराव को उसमें शामिल नहीं किया गया. फिर कैप्टन के पद पर 1985 में उनकी पदोन्नति भी छह महीने देर से हुई. इस सब से दुखी होकर सुब्बाराव ने समय-पूर्व अवकाश ग्रहण करने का फैसला किया और दो साल बाद अक्तूबर 1987 में ही उन्हें इसकी मंजूरी मिल पाई.

लेकिन अवकाश ग्रहण करने के बाद भी सुब्बाराव नेवी नगर में तेरहवीं मंजिल पर मिले अपने सरकारी फ्लैट में परिवार सहित रहते रहे. अप्रैल में दिल्ली आकर उन्होंने नौसेना से परामर्शदाता के रूप में जुड़े रहने की संभावनाओं के बारे में वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, शर्त यह थी कि उन्हें उसी फ्लैट में रहने दिया जाए. विडंबना ही है कि बंबई में गिरफ्तारी वाले दिन ही उन्हें नौसेना मुख्यालय से एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें 'सूक्ष्म तरंग संचार साधनों पर पर्यावरण के प्रभाव के पूर्वानुमान' से संबंधित कार्यक्रम में उनका सहयोग मांगा गया था.

इसके अलावा सुब्बाराव ने जहाजों और पनडुब्बियों के लिए अति चालकता नोदन प्रणाली की भी पेशकश की थी जिसका प्रारूप उन्होंने खुद तैयार किया था. उन्होंने यह प्रारूप भारतीय अति चालकता कार्यक्रम के अध्यक्ष सी.एन.आर. राव को भेजा था. इसके अलावा सुब्बाराव को सी-डॉट द्वारा विकसित टेलीफोन एक्सचेंज के नमूने का विश्लेषण करने के लिए भी कहा गया. उनका दावा है कि तकनीकी मिशन के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने उन्हें उच्च पद देने की पेशकश की थी.

गिरफ्तारी के बाद सुब्बाराव ने दिल्ली से आए वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों को बताया कि कुछ दस्तावेजों पर अंकित 'अति गोपनीय' शब्द उनका अपना लिखा हुआ है, सरकारी दस्तावेज से उसका कोई ताल्लुक नहीं. इन दस्तावेजों में दर्ज जानकारी गोपनीय भी नहीं है. इसका कुछ हिस्सा तो वे नौसेना की अनुमति से अपनी पीएचडी थिसिस में भी इस्तेमाल कर चुके हैं.

प्रतिभा के धनी सुब्बाराव आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक जुलाहा परिवार से हैं. हालांकि वे इंजीनियरिंग के स्नातक हैं पर नौसेना में काम करते-करते, स्वध्याय के बल पर उन्होंने उच्च गणित और कंप्यूटर सिद्धांत भी सीख लिए. उनकी उपलब्धियों को दो बार सरकारी मान्यता भी मिल चुकी है. 1978 में उन्हें हरबर्ट लॉट मेमोरियल अवार्ड मिला और 1983 में नौसेना ने उन्हें कंप्यूटर तकनीक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विशिष्ट योगदान के लिए स्वर्ण पदक दिया. लेकिन नौसेना के इस पूर्व कप्तान के शानदार कैरियर ने अब एक दुखद मोड़ ले लिया है.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिर्फ़ प्यार ही नहीं चुका सकता इनकी दवाओं के बिल.

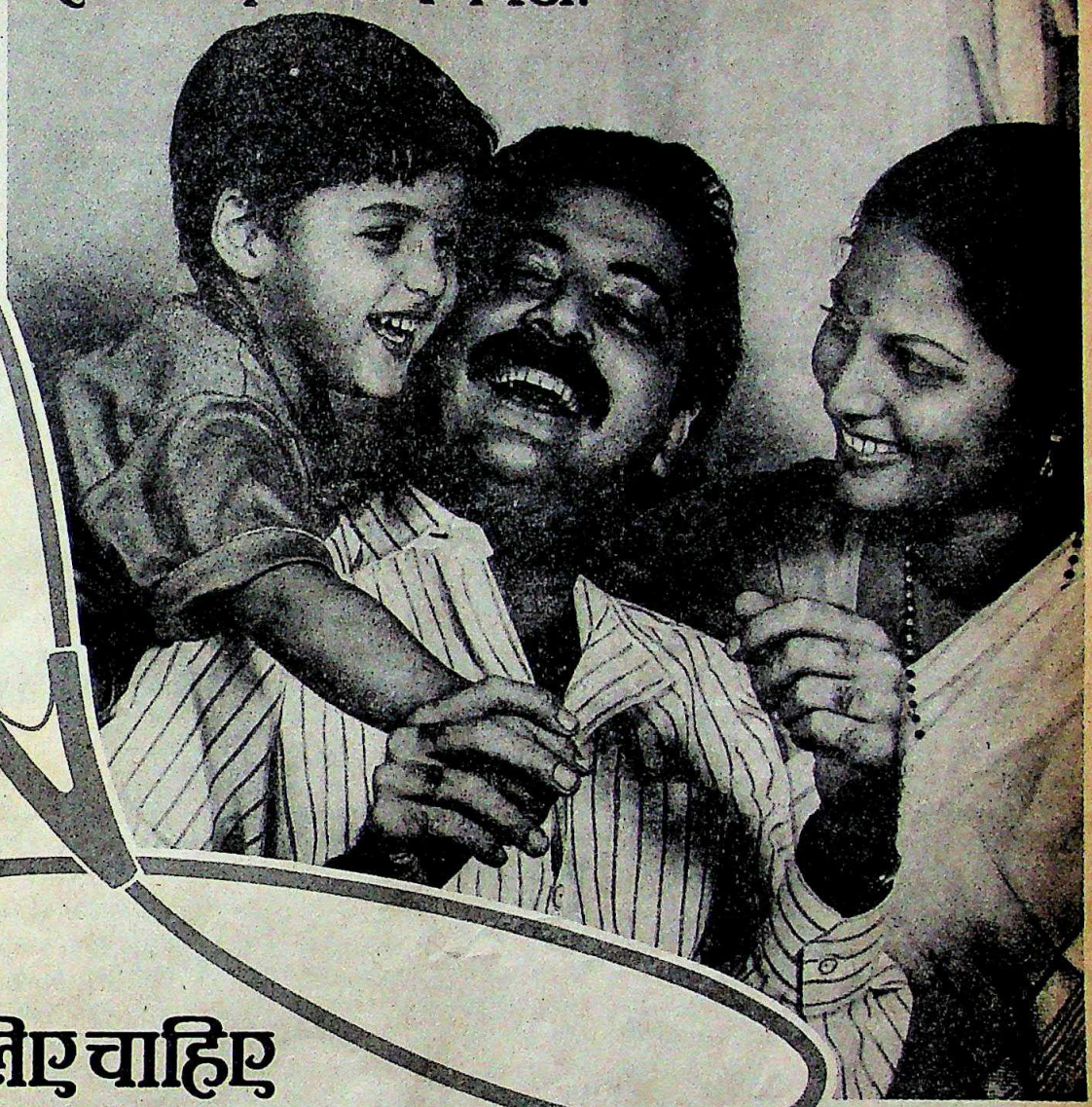

इसके लिए चाहिए मेडिक्लेम.

जी हां, मेडीक्लेम की हॉस्पिटलाइज़ेशन और डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन बेनिफ़िट पॉलिसी आपके परिवार के लिए है एक अनोखा वरदान.

आपका ढेर सा प्यार...आपकी कंपनी की कोई भी मेडीकल योजना.... बड़ी-बड़ी बीमारियों, ऑपरेशन और दुर्घटना में इलाज पर होने वाले खर्च का बिल नहीं चुका सकती.

इसीलिए आपको चाहिए मेडीक्लेम. मेडीक्लेम के ज़रिए आप कई तरह के चिकित्सा लाभ हासिल कर सकते हैं– वह भी आपकी आवश्यकता, आपकी ज़रूरतों के अनुरूप.

यहां तक कि आप घर पर रहकर इलाज करने का खर्च भी पा सकते हैं.

साथ ही आप पारिवारिक-छूट और करों में छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.

यदि आप अपने परिवार को सही मायने में प्यार करते हैं तो मेडीक्लेम योजना के अंतर्गत इनका बीमा कराइए.

जो आपको कम खर्च में दिलाए कहीं ज़्यादा सुरक्षा, कहीं ज़्यादा लाभ और यही है आपके प्यार का सच्चा सुबूत.

प्रीमियम प्रति वर्ष रु.	हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.	डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.
२००	१०,५००	३,१००
२५०	१७,६००	–
३५०	२५,५००	–
६०० *	३७,७५०	५,२५०
८४० *	५२,७५०	७,४००
१,३०० *	८२,५००	११,५००

★ *अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध.*

MEDICLAIM

मेडीक्लेम के प्रस्तुतकर्ता न्यू इंडिया एश्योरन्स

NEW INDIA ASSURANCE

A subsidiary of the General Insurance Corpn. of India

ख़तरे का कोई भी नाम.... बीमा करना हमारा काम.

CONTOUR ADS-NIA-2788/87 HIN

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिखाने के दांत

इस्पात कारखाने, टेलीविजन केंद्र और राष्ट्रीय समाचार एजेंसी वगैरह कभी विकासशील देशों के लिए उन प्रतीकों में शुमार थे जिन्हें स्टेटस सिंबल यानी हैसियत का चिन्ह माना जाता है. हिंदुस्तान के बड़े अखबारों में विदेश संवाददाताओं की स्थिति लगभग वैसी ही है. आजादी के 40 वर्षों बाद भी भारतीय पत्रकारिता का दुखद पहलू यह है कि कुछेक अपवादों को छोड़कर ज्यादातर विदेश संवाददाता दिखाने के दांत ही हैं.

भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संवाददाता दूसरी श्रेणी में आते हैं. उनकी हैसियत भारतीय कूटनीतिज्ञ सरीखी होती है और राजदूत भी उनसे ऐसा ही बरताव करते हैं. उनकी तनख्वाह आदि प्रथम सचिव के बराबर होती है. जाहिर है सरकार उन्हें अहमियत देती है.

विदेशों में भारतीय अखबारों के संवाददाताओं को देखने से जाहिर होता है कि भारतीय नजरिये से महत्वपूर्ण देशों को उपेक्षित ही छोड़ दिया गया है. पाकिस्तान में किसी भारतीय संवाददाता की नियुक्ति तो दोनों सरकारों की मर्जी पर निर्भर है लेकिन भारत के लिए अहमियत रखने वाली दो राजधानियों मॉस्को और बीजिंग में किसी भी बड़े अखबार ने अपना संवाददाता नियुक्त करने पर कभी गौर नहीं किया.

वाशिंगटन और लंदन में भारतीय संवाददाताओं का बेवजह ही हमेशा भारी जमावड़ा लगा रहा है. बेवजह इसलिए क्योंकि ज्यादातर अखबार अपने इन संवाददाताओं को ज्यादा यात्रा करने की अनुमति नहीं देते. इसका नतीजा यह होता है कि वे स्थानीय अखबारों और टीवी रिपोर्टों के आधार पर अपनी रिपोर्टें भेजते रहते हैं.

इंग्लैंड से हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं इसलिए थोड़ी छूट ले भी लें. मगर फिर भी लंदन में भारतीय संवाददाताओं की पूरी फौज ही तैनात हो यह बहुत उपयुक्त नहीं लगता. इंग्लैंड - दुनिया में ज्यादा-से-ज्यादा दोयम दर्जे की ताकत ही तो है. और ज्यादा दिलचस्प व महत्वपूर्ण घटनाएं तो फ्रांस और पश्चिम जर्मनी में घटती रहती हैं. मगर लंदन स्थित भारतीय संवाददाता शायद ही कभी इंग्लिश चैनेल पार करने की जहमत उठाते हैं. कोई भारतीय मंत्री दौरे पर पहुंचा हो तो अलग बात है. वरना वे आम तौर पर यूरोप की खबरें ब्रिटिश चश्मे से परखकर भेजते रहते हैं.

लेकिन इस सनक में भी चतुराई छिपी हुई है. ज्यादातर अखबार बस यही चाहते हैं कि संसार की कुछ चुनिंदा राजधानियों से खबरें भारतीय संवाददाताओं के नाम से छपती रहें. वे अपने संवाददाताओं को यात्रा करने के लिए बहुत थोड़े पैसे ही मुहैया कराते हैं. इसी वजह से संवाददाता विदेशों में बसे भारतीयों और भारत के साथ उस देश के रिश्तों की खबरों तक ही अपने आपको सीमित रखते हैं. पाकिस्तान से संबंधित कोई भी खबर पहले पेज का मसाला होती है क्योंकि इस मामले में हमारा राष्ट्रप्रेम तुरंत जाग उठता है. और यदि भारत से संबंध न रखने वाली किसी बड़ी घटना को टालना संभव न हो तो वहां के अखबार तो हैं ही खबर 'चुराने' के लिए.

भारतीय अखबारों में विदेश संपादक जैसा कोई पद है ही नहीं. इसी से जाहिर है कि विदेश संवाददाता महज दिखाने के दांत ही हैं. उसे रोजाना सलाह देने या उससे संपर्क करने वाला कोई नहीं होता. और अब तो यह एक परंपरा-सी बन गई है कि संवाददाता संसार भर की खबरों का आकलन भारतीय नजरिये से करता है जबकि उसे विचारों के रूप में सारा कच्चा माल विकसित देशों से मिलता है. इस तरह अखबार के प्रबंधकों की कंजूसी और संवाददाताओं का आलस दोनों के संयोग से घाटा पाठकों को ही होता है.

भारतीय अखबार इस तरह बेवजह ही विदेश संवाददाताओं का बोझ लादे रहते हैं. उनको दिया पैसा फिजूल ही जाता है क्योंकि वे वही खबरें देते हैं जो समाचार एजेंसी भी देती है. दरअसल उनका काम प्रमुख घटनाओं का आकलन और संबंधित क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत करके वहां की परिस्थितियों की दशा और दिशा की जानकारी देना होना चाहिए. इसके लिए प्रयास और पैसे की जरूरत होती है जिनकी अमूमन कमी रहती है.

कार्टून: अजीत नैनन

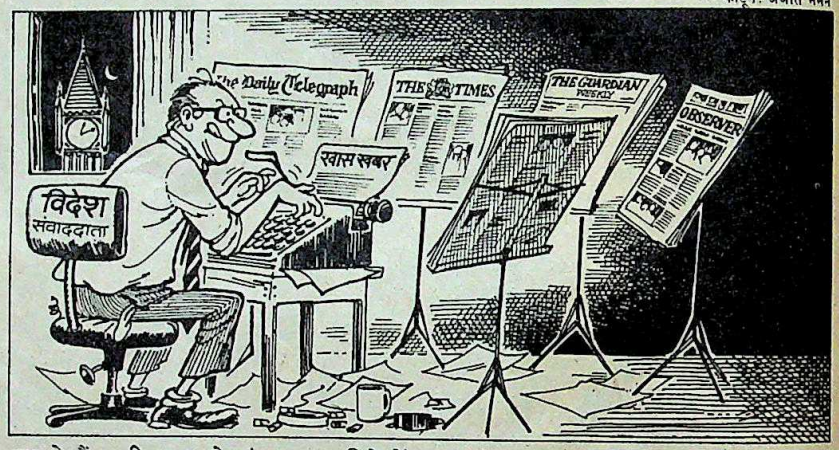

हां, अगर प्रधानमंत्री वहां के दौरे पर हों तो भारतीय विदेश संवाददाता की सक्रियता देखते ही बनती है. उसके अखबार के प्रबंधक भी तब उसकी यात्राओं का खर्च उठाने के लिए अपना खजाना खोल देते हैं. और उन चंद दिनों में वह बेहिसाब खबरें भेजता है और प्रायः सबकी सब पहले पन्ने पर छपती हैं. इसके बाद वह फिर अपने पुराने ढर्रे पर या तो पाकिस्तान के नए हथियारों के जखीरे अथवा विदेशों में भारत की बढ़ती साख पर खबरें भेजना शुरू कर देता है.

लेकिन भारतीय विदेश संवाददाताओं में कुछेक अपवाद भी हैं. 'द हिंदू' के मध्य-पूर्व संवाददाता एफ. जे. खेरगामवाला का नाम इस संदर्भ में लिया जा सकता है. वे हमेशा सक्रिय रहते हैं. अपने क्षेत्र के बारे में उनके आकलन पढ़ने के काबिल होते हैं. वहां की घटनाओं और हस्तियों के बारे में उनकी टिप्पणियां बहुत संतुलित होती हैं. वे अपने देश के महत्व पर अतिशयोक्ति नहीं करते. इसका एहसास प्रधानमंत्री की हाल की सीरिया यात्रा पर उनके आकलन और प्रधानमंत्री के साथ गए संवाददाताओं की रिपोर्ट की तुलना करने से होता है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

सहमे नौनिहाल

दहशत में डूबी कलम-कूची

आदरणीय गुरु नानक जी,

आपका पता कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूं कि आप हमारे दिलों में बसते हैं. आप तो जानते ही हैं कि देश के हालात बहुत खराब हैं. आतंकवाद चारों ओर फैल रहा है. आज भाई भाई से लड़ रहा है और लोग एक-दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं. हर किसी के दिल में दरार डाली जा रही है. काश! आप यहां होते. आज इस दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है.

आपकी अपनी बेटी
नवजोत कौर

जालंधर की १३ वर्षीया नवजोत कौर की यह चिट्ठी इस बात का प्रमाण है कि पंजाब के नौनिहाल आज कितने सहमे हुए हैं. जालंधर में कुछ दिनों पहले 8-14 साल के बच्चों के लिए आयोजित एक पत्रलेखन प्रतियोगिता में शरीक हुए 150 बच्चों में नवजोत भी एक थी. बाकी बच्चों के पत्रों से भी कमोबेश वही चिंता झलकती है जो नवजोत के पत्र में दिखती है.

और यही चिंता उन बच्चों के चित्रों में अंकित दिखी जो चंडीगढ़ की एक स्वयंसेवी संस्था 'सारंग' द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में शरीक हुए थे. आठ वर्षीया निलि कौर ने जो चित्र बनाया उसमें हरे-भरे खेतों और नीले आकाश की चटख पृष्ठभूमि में पांच आदमी थोड़ी-थोड़ी दूर पर खड़े थे. उनमें से तीन के हाथ में गुलाब का फूल, तोता और पेड़ था तो दो लोग काली पिस्तौलें ताने डरावनी मुद्रा में खड़े थे.

बंदूकों का यह खौफ बच्चों के मानस में गहरे पैठ गया दिखता है. भावना, नेहा, रोहन—छह से नौ वर्ष की आयु के इन बाल कलाकारों ने बादल, पहाड़, पेड़, नदी और बत्तखों की सुहावनी पृष्ठभूमि में हथियार उठाए आतंकवादियों को चित्रित किया था. प्रतियोगिता में शरीक 50 में से आधे से ज्यादा बच्चों ने अपने चित्रों में या तो बंदूक ताने आतंकवादी दिखाए या खून के धब्बे. उन्हें जो विषय दिया गया था, वह था 'हमारा पंजाब' या 'पंजाब की एक यात्रा'.

कुछ बच्चों ने पंजाब के खुशहाल जीवन, ग्रामीण मेलों, चहल-पहलभरी सड़कों आदि के चित्र बनाए तो उनमें भी आतंकवादी हत्याओं की दहशत की छाप स्पष्ट थी. सबसे मर्मस्पर्शी चित्र चंडीगढ़ के हरीश का था जिसने स्वर्णमंदिर के बनाए चित्र में दो शव दिखाए थे—एक मंदिर की परिक्रमा में, दूसरा पवित्र सरोवर के जल में.

लेकिन बच्चों के मानस पटल पर आतंकवादियों की जो तस्वीर है, उसमें न तो उनके दाढ़ी है, न पगड़ी. यानी एक आम सिख और आतंकवादी का अंतर उनके मन में स्पष्ट है. दो बच्चियों ने आतंकवादियों के बनाए चित्रों में सिरों पर सींग बना दिए थे.

जालंधर के सरकारी माध्यमिक स्कूल की मीना ने गुरु नानक को लिखे अपने पत्र में शिकायत की, "धार्मिक झगड़े, जो आपने तब निबटा दिए थे, फिर से शुरू हो गए हैं. आतंकवादी लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं. दंगे भड़क रहे हैं. आप इन धार्मिक झगड़ों को मिटा दीजिए." पत्रलेखन प्रतियोगिता की आयोजक संस्था चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के राम रतन कहते हैं, "बच्चों के दिमाग अभी सांप्रदायिकता के जहर से अछूते हैं."

आठवीं कक्षा की छात्रा आरती सग्गी को तो पूरा भरोसा है कि पंजाब की इस दुरावस्था का एकमात्र हल गुरु नानक के उपदेशों पर अमल है. वह पूछती है, "यदि हम सब मिलकर रहें और सचाई पर चलें तो क्या आतंकवाद टिक सकता है?" ज्यादातर बच्चे गुरु नानक को मसीहा अथवा भगवान नहीं बल्कि परिवार का एक स्नेही बुजुर्ग मानते हैं. बच्चों की इन प्रतिक्रियाओं में उल्लेखनीय बात यह है कि बरसों से चला आ रहा आतंकवाद उनकी उम्मीदों और आस्थाओं को डिगा नहीं पाया है.

—विपुल मुद्गल

बच्चों द्वारा बनाए चित्रः आतंक की छाया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

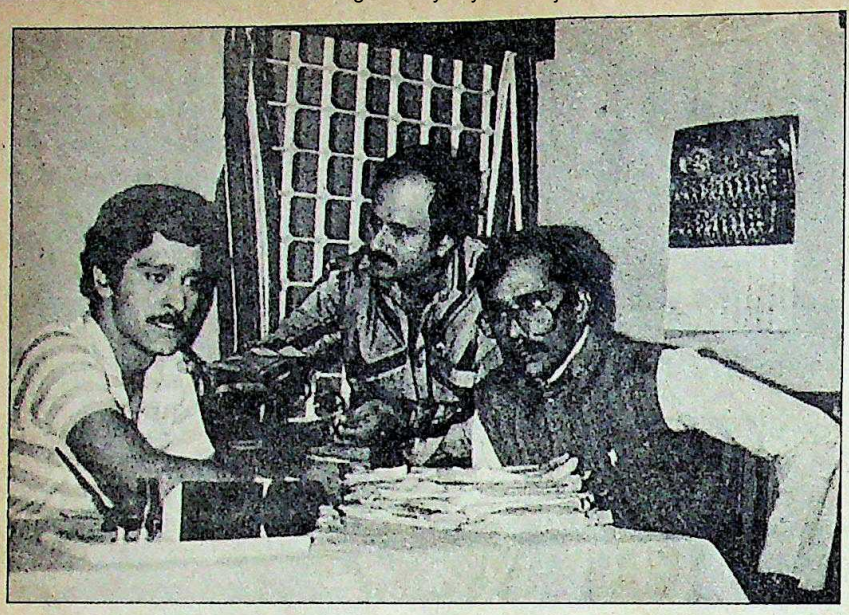

कभी 'गुनाहों का देवता' (बाएं) जैसे उपन्यास पर अच्छे नाटक बने, आज तो बस फूहड़ हास्य, सतही अभिनय (दाएं) ही बचा है

नाटक

सुधार के लिए अंततः चेते

हिंदी टीवी नाटकों के स्तर में सुधार के लिए साहित्यकारों की बैठक

उस दिन दूरदर्शन महानिदेशालय में अपूर्व नजारा था. दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जालंधर, अमृतसर और पटियाला के कई हिंदी साहित्यकार वहां जुटे थे. जाहिर है मसला गंभीर था.

दूरदर्शन के आकाओं की चिंता का सबब था पाकिस्तानी टीवी नाटकों की लोकप्रियता और अपने दूरदर्शन के नाटकों का गिरता स्तर और गिरती साख. अब इसी के पुनरुद्धार के लिए हिंदी लेखकों को तलब किया गया था. यानी यह एक तरह से अपनी असफलता की आत्मस्वीकृति ही थी. बहरहाल, 16 मई को हुई बैठक में मुद्राराक्षस, डी.पी. सिन्हा, इकबाल मजीद, गिरिराज किशोर, हरचरण सिंह, गुरशरण सिंह, के.के. नैयर, रेवतीशरण शर्मा, चिरंजीत, मन्नू भंडारी, कांति देव, बी.एम. शाह, रमेश बख्शी, असगर वजाहत और डॉ. मुहम्मद हसन वगैरह शरीक हुए.

दूरदर्शन के उपमहानिदेशक अलबेल सिंह गरेवाल कहते हैं, "हमने बंबई वगैरह से और भी हिंदी लेखकों को बुलाया था, पर समय की कमी के कारण कुछ लोग पहुंच नहीं सके. हिंदी के लेखकों को ही इसलिए बुलाया कि समस्या हिंदी नाटकों की ही है. तमिल, तेलुगु या बंगला में दूरदर्शन के नाटक ठीक ही जा रहे हैं. लेखकों के बाद नाट्य समूह के निर्माताओं के साथ भी बैठक की जाएगी. फिर आखिर में अपने स्टाफ के लोगों के साथ." लेकिन ये बैठकें कब की जाएंगी इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ बताने से गरेवाल ने इनकार किया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इधर हम कुछ दूसरे कामों में व्यस्त रहे इसलिए कुछ तय नहीं हो पाया है. लेकिन जल्द ही इस दिशा में कोई कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली, लखनऊ, जालंधर और श्रीनगर केंद्र हिंदी-उर्दू नाटकों को बनाने वाले मुख्य केंद्र हैं. पर ये चार केंद्र मिलकर भी अब चार नाटक नहीं बनाते. एक तो नाटकों का गिरता स्तर, ऊपर से नए नाटकों का निर्माण न होने से दर्शकों को घटिया नाटकों के 'रिपीट शो' मिलते रहते हैं. पिछले दिनों में 'बैसाखी', 'बदलते रिश्ते' जैसे दो-चार ही अच्छे नाटक दिल्ली दूरदर्शन बना सका है और वह भी टेलीफिल्म के रूप में. बाकी केंद्रों में भी साल-दो-साल में शायद ही कोई अच्छा नाटक आ पा रहा है जो दर्शकों पर प्रभाव छोड़ता हो.

बहरहाल, नाटकों में सुधार की जरूरत के प्रति चिंता कितनी प्रबल है यह 16 मई को महानिदेशालय के 'कान्फ्रेंस हॉल' में हुई उस बैठक में महानिदेशक भास्कर घोष के शब्दों में व्यक्त हुई, "हम चाहते हैं पाकिस्तानी टीवी जैसे नाटक हमारे यहां भी बनें. इसके लिए 'हार्डवेअर' और 'साफ्टवेअर' में जो करना होगा हम करेंगे."

लेखकों में सबसे पहले बोले धारावाहिक 'और भी गम हैं जमाने में', 'लेना-देना' आदि के लेखक रेवतीशरण शर्मा. उनका कहना था कि पाक टीवी भरपूर सुविधाएं देता है इसीलिए नाटकों का स्तर अच्छा है. वहां फिल्में इतनी लोकप्रिय नहीं हैं इस कारण नाटककार अपनी पूरी प्रतिभा टीवी नाटकों में ही लगा देते हैं. पाकिस्तानी टीवी नाटकों की लोकप्रियता के बारे में उनका कहना था कि वे गुलशन नंदा के उपन्यासों की तरह हैं जिनमें रोमांस की प्रमुखता होती है. लेकिन हमें वैसी सुविधाएं मिलें तो हमारे यहां के नाटक पाकिस्तानी टीवी से अच्छे बन सकते हैं क्योंकि हमारे यहां सामाजिक मुद्दों को उठाने की छूट है जबकि वहां नहीं है. लेकिन इसके लिए जाहिर है सरकारी तंत्र में बदलाव लाने होंगे. बदलावों के संदर्भ में उनका सुझाव था कि केंद्र निदेशक को बजट वगैरह के लिए पूरे अधिकार मिलने चाहिए. कला निदेशक बाहर से लेना चाहिए. उनकी मांग यह भी थी कि नाटकों की शूटिंग अक्सर देर रात तक होती है सो अतिरिक्त वक्त के लिए निश्चित तौर पर अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए.

शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि दिल्ली दूरदर्शन ने पिछले 20 साल से किसी लेखक को नहीं बुलाया. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुतियों को ही ले लिया जाता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मां जागी' के लेखक चिरंजीत ने हिदायत के लहजे में कहा कि "आप लोग पहले अपने घर को ठीक कीजिए." उन्हें अफसोस था कि लेखक-निर्माता और निर्देशक में सही तालमेल नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेखक अपना नाटक टीवी पर देने के लिए हाजिरी लगाता फिरता रहे. उनका कहना था कि कोई भी अच्छा लेखक दूरदर्शन पर आने से इसलिए कतराता है कि उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए

मगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रानावि) रंगमंडल के प्रमुख जे.एन. कौशल को दूरदर्शन के नाटक महज खानापूरी लगते हैं, "जितना 'होम वर्क' होना चाहिए वह नहीं होता. बाहर का 'टैलेंट' यहां इसलिए नहीं आता कि पैसा बहुत कम है. यहां एक लंबे नाटक के लिए अगर 2500 रुपए मिलते हैं तो बाहर 25,000 रुपए मिल जाते हैं." उनका सुझाव है. दूसरे, नाटकों के बेहतर न बनने में प्रशासनिक दोष बहुत हैं. उनका सवाल था, "सागर जिस तरह की सुविधाओं में 'रामायण' बना रहे हैं क्या वैसी सुविधाएं मुझे नाटक बनाने के लिए दी जाएंगी? टीवी अपने प्रोडक्शन को 'प्राइम टाइम' नहीं देता. नाटकों को शाम 7.40 का समय दिया गया है जो कि दर्शकों के लिए कतई उपयुक्त नहीं है. रात 9.50 का समय भी हमको तब मिलता है जब कोई प्रायोजित कार्यक्रम उस समय न हो."

'रानावि' के लोगों को ही लेकर नाटक करने और बाहर के लेखकों को न बुलाने तथा दूरदर्शन के लोगों के बाहर काम करने पर वेद सिन्हा कहती हैं, "जब सीरियल वगैरह में भी फिल्म के लोग आ गए हैं तब 'रानावि' के लोग कहां जाएं. उन्हें हम नाटकों में लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं. बाहर से लेखकों को बुलाने का साहस हम कैसे करें. उन्हें इतना कम पैसा दिया जाता है कि हम किसी को कुछ करने के लिए कह ही नहीं सकते." बाहर काम करने के मामले में सिन्हा का कहना था कि "यदि बाहर कोई इज्जत देकर बुलाए, काम की भी कद्र करे और पैसे भी अच्छे दे तो बाहर का काम क्यों नहीं करना चाहिए."

यानी दूरदर्शन के प्रशासनिक ढांचे में वाकई काफी खामियां हैं. लेखक, निर्माता, निर्देशक और दर्शक अपनी-अपनी जगह सही लगते हैं. शुक्र है दूरदर्शन महानिदेशक ने सभी के जख्मों पर मरहम लगाने में पहल की है. यहां उल्लेखनीय बात यह है कि भास्कर घोष खुद भी कुछ वर्ष पहले बतौर अभिनेता और निर्देशक नाटकों में काम कर चुके हैं. इसलिए उम्मीद है नाटकों के प्रति उनकी चिंता का कुछ रचनात्मक नतीजा जरूर निकलेगा.

वैसे चार साल पहले भी सूचना और प्रसारणमंत्री हरकिशन लाल भगत ने 100 के करीब हास्य लेखकों की बैठक की थी और फिर उसके बाद बात खास आगे नहीं बढ़ी थी. अब फिर भगत इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं. लेकिन इस बार भी अगर बात बैठक से आगे न बढ़ी तो यही कहना पड़ेगा कि यह सब नाटकों के प्रति हमदर्दी का नाटक भर ही था.

—प्रदीप सरदाना

"सागर जिन सुविधाओं से 'रामायण' बना रहे हैं क्या वैसी सुविधाएं मुझे नाटक बनाने के लिए दी जाएंगी?"

वेद सिन्हा
ड्रामा प्रोड्यूसर, दूरदर्शन

"हमारे नाटकों में दार्शनिकता इतनी है कि वे जिंदगी के नाटक नहीं लगते. हास्य-व्यंग्य भी बेहद बचकाना होता है."

कांति देव
हिंदी लेखिका

उन्होंने इस बात पर भी रोष व्यक्त किया कि टीवी प्रोड्यूसर लंबी-लंबी छुट्टियां लेकर बाहर के काम करते हैं.

'बैसाखी', 'चिंगारी' 'दीमक' वगैरह की लेखिका कांति देव को पाकिस्तानी टीवी नाटकों में कोई नई धारा, नई क्रांति नहीं दिखी, लेकिन इन नाटकों में उन्हें जीवन का अक्स दिखता है. दूसरी ओर "हमारे यहां नाटकों में हास्य इतना फूहड़ है कि बच्चे भी उस पर मजाक करते हैं. यहां नायक-नायिका को ही चुनने पर ध्यान दिया जाता है, बाकी कलाकारों पर नहीं. इन नाटकों में दार्शनिकता इतनी होती है कि वे अपनी जिंदगी के नाटक लगते ही नहीं."

लेकिन प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी ने बैठक में अपनी भागीदारी के बारे में कहा, "मैं कुछ ज्यादा बोली नहीं, शुरू में काफी देर यही बात चलती रही कि पाकिस्तानी नाटक लोकप्रिय क्यों हैं. मैंने कोई खास पाकिस्तानी नाटक देखे नहीं सो मैं चुप रही. हां, यह जरूर कहा कि नाटक अच्छे नहीं बन रहे हैं. पर मुझे लगा घोष साहब कुछ करना चाहते हैं. पहले उम्मीद थी टीवी में फिल्मों से हटकर नया कुछ देखने को मिलेगा लेकिन अब यहां भी व्यावसायिकता हावी हो गई है."

दूरदर्शन का पहला नेटवर्क सीरियल 'दादी था कि आज यदि अच्छे नाटक नहीं लिखे जा रहे तो पुराने नाटकों या उपन्यासों को रूपांतरित किया जा सकता है. नाटकों को लोकप्रिय बनाने के लिए टीवी को चाहिए कि एक तो वह इनका समय दस बजे से पहले का रखे. दूसरा, अंग्रेजी 'सब टाइटल्स' भी दे. इससे दर्शक संख्या में बढ़ोतरी होगी.

दूरदर्शन की ड्रामा प्रोड्यूसर वेद सिन्हा को लगता है कि व्यावसायिक कार्यक्रमों के कारण नाटकों की लोकप्रियता में कमी आई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंदी फिल्में

नायिका के नए तेवर

सरसों के सुनहरे खेतों के बीच गाना गाते हीरो के साथ नाचती-कूदती गांव की वह भोली-भाली लड़की या अपने प्रेमी के लिए सब कुछ लुटा देने और विरह-वियोग को चुपचाप सह लेने वाली शहरी औरत आखिर कहां चली गई? हिंदी सिनेमा की नायिका ने क्या एकाएक बदले की आग में धधकती एक कठोर औरत का रूप ले लिया है? क्या अब वह रुपहले परदे पर छा जाने के लिए नायक को किनारे करने लगी है?

हरमेश मल्होत्रा की फिल्म 'शेरनी' में श्रीदेवी गांव की एक जिंदादिल किशोरी न रहकर एक क्रूर और दहशत फैला देने वाली औरत बनकर उभरती हैं, जो काले लिबास में अपने परिवार के संहार का बदला लेने निकल पड़ती है. राकेश रोशन की 'खून भरी मांग' में भोली-भाली और कर्तव्यनिष्ठ रेखा दो बच्चों की मां बनी हैं. एक पुरुष उसका शोषण करता है. लेकिन वह विदेश जाकर एक खूबसूरत और बेहद सफल फैशन मॉडल बन जाती है तथा अपमान का बदला चुकाने के लिए स्वदेश लौटती है.

अवतार भोगल की 'जख्मी औरत' में शुरू से लगता है कि मोटरसाइकिल सवार पुलिस इंस्पेक्टर डिंपल कपाड़िया को अपने काम के प्रति मोह है. यह पुलिस इंस्पेक्टर जबरदस्त घूंसेबाजी करती है, गुंडों को कराटे के एक ही वार से चित कर देती है और खुलेआम अपने रिवाल्वर का इस्तेमाल करती है. लेकिन उसके अंदर की सचमुच की फौलादी औरत तब प्रकट होती है जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है. वह इस हादसे को भूलकर शादी रचा लेने की अपने प्रेमी की सलाह ठुकरा देती है और शहर के सभी बलात्कारियों को चुन-चुन कर बधिया करने में ही अपनी सारी जिंदगी लगा देती है.

यह अप्रत्याशित भले ही न हो पर हिंदी फिल्मोद्योग की कल्पनाशील प्रयोगशालाओं में एकाएक एक नए फार्मूले का उद्भव हुआ है जिसमें एक कठोर, हठी और अक्सर बदले की आग में झुलसती उस भारतीय नारी का चित्र उभरता है जो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहते हुए अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करने वाली नहीं है. इस फार्मूले के साथ ही 'नारी प्रधान' फिल्मों को लेकर बनाई जाने वाली इन फिल्मों में परदे पर नायिका ही छाई रहती है. लगभग 10 'नारी प्रधान' फिल्मों में काम कर रही रेखा कहती हैं, "अब वक्त बदल गया है. पहली दफा नायिका एक ऐसी कठोर और निर्मम औरत के रूप में सामने आई है जो बुराइयों से मुकाबला करना चाहती है. यही आज की भारतीय नारी की छवि है."

पीटर मार्टिस/स्कीन

बंदूकधारी श्रीदेवी: बाकियों के लिए आदर्श

निस्संदेह, हर कोई जानता है कि अकेले ही जूझने वाली इस औरत का जन्म कहां से हुआ है. यह महबूब की उत्कृष्ट फिल्म 'मदर इंडिया' की उपज नहीं जिसमें नायिका को सहानुभूति बटोरती है, बल्कि यह एन. चंद्रा की बेहद सफल फिल्म 'प्रतिघात' की उपज है. एक अनजान अभिनेत्री को लेकर बनाई गई इस फिल्म में कॉलेज की एक अध्यापिका सार्वजनिक तौर पर निर्वस्त्र किए जाने का बदला लेती है. हाल के वर्षों में यह धुआंधार पैसा बटोरने वाली फिल्मों में से एक रही.

फिल्म निर्माता जहां ऐसी फिल्मों के लि श्रीदेवी, डिंपल, रेखा और हेमा मालि सरीखी उच्च कोटि की तारिकाओं से दनाद अनुबंध कर रहे हैं जिनमें उनकी ही मु भूमिका होगी, वहीं फिल्मोद्योग यह अ लगाए बैठा है कि शायद इसी फार्मूले बॉक्स ऑफिस की कमाई फिर से बढ़ जा उधर फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं नारी प्रधान फिल्मों के समर्थक भी हैं आलोचक भी. मल्होत्रा, जिनकी 'शेरनी' श्रीदेवी को ही लेकर बनाई गई पहले वा फिल्म 'नगीना' जैसी सफलता हासिल कर पाई, कहते हैं, "हिंसा और बदले वा फिल्म महिलाओं को भी भाने लगी महिलाओं समेत लोग अब लिजलिजे पा को देखना पसंद नहीं करते." चंद्रा कहते "हिंदी सिनेमा में औरत की छवि धीरे-धी बदल रही है. पहले उसे ममता की मूर्ति रूप में सामने आना होता था. अब उस लिए संहारक सरीखी छवि की जरूरत है चंद्रा 'तेजाब' नामक फिल्म बना रहे हैं जि माधुरी दीक्षित एक विद्रोही और स्वाभिमा औरत की भूमिका निभा रही हैं.

लेकिन डिंपल और अमृता सिंह सरी अभिनेत्रियां अनेक निर्माणाधीन नारी प्र फिल्मों को आनंददायक, मगर अस्व घटनाक्रम मानती हैं. ऐसी तकरीबन दर्जन फिल्में इस साल के आखिर तक प्रद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नामस भोजानी

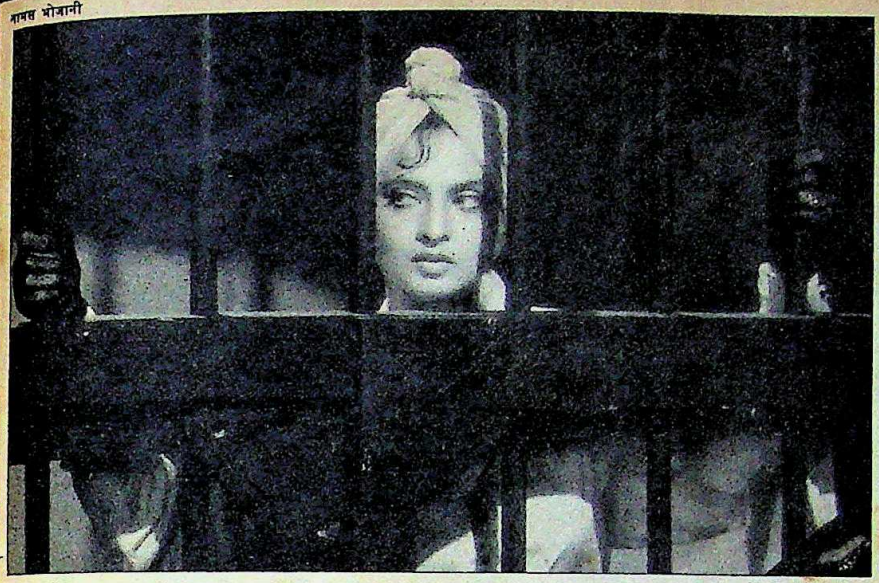

स्क्रीन

स्क्रीन

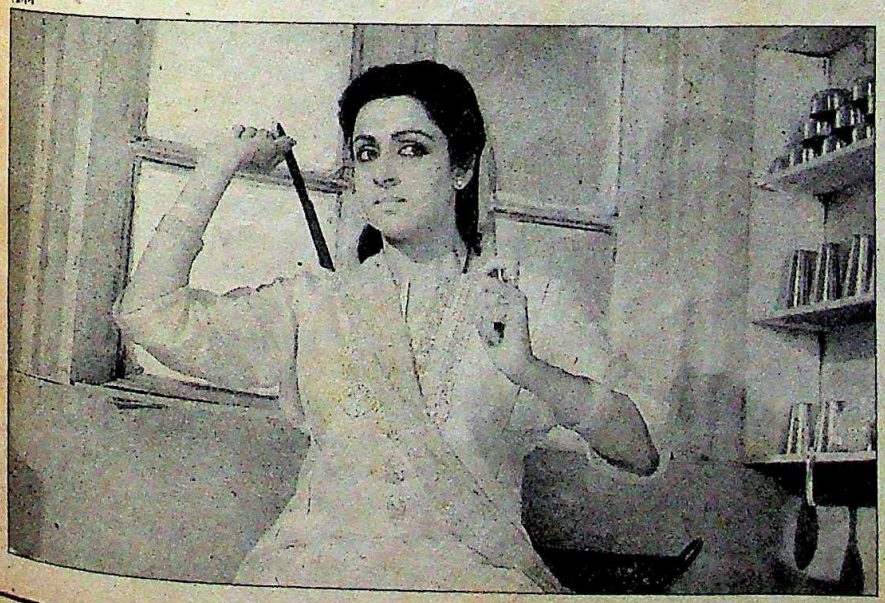

भी हो जाएंगी. डिंपल कहती हैं, "लोग इन फिल्मों को बेमतलब अहमियत दे रहे हैं. हिंदी सिनेमा में इनका बोलबाला नहीं होगा." 'खून बहा गंगा में' की डकैत नायिका अमृता सिंह भी कहती हैं, "हमारा पुरुष प्रधान समाज है. सच कहें तो श्रीदेवी जैसी अभिनेत्री ही नारी प्रधान फिल्मों में सफल हो सकती हैं." आलोचक इकबाल मसूद और स्पष्ट ढंग से कहते हैं, "यह प्रवृत्ति श्रीदेवी के साथ ही खत्म हो जाएगी. ये फिल्में कोई ऐसा मिथक स्थापित नहीं करतीं जो किसी टिकाऊ फार्मूले में मददगार साबित हो सके."

श्रीदेवी और डिंपल सरीखी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ ही नारी प्रधान फिल्में भी व्यावसायिक शिखर पर पहुंचीं. पर कठोर और हठी औरत की छवि दरअसल 70 के दशक में उभरे नए सिनेमा की ही देन है जो शबाना आज़मी और स्मिता पाटील जैसी अभिनेत्रियों को आगे लाया. पहली बार हिंदी सिनेमा औरतों पर गंभीरता से ध्यान देने पर मजबूर हुआ. हिंदी सिनेमा की उस नई लहर के सबसे कामयाब निर्देशक श्याम बेनेगल मानते हैं कि इन फिल्मों की औरतें उस शाश्वत संवेदनशीलता का ही विस्तार हैं जिसे नरगिस ने 'मदर इंडिया' में बखूबी परदे पर उतारा था.

यह फार्मूला टिकाऊ साबित हुआ है या नहीं, पर बंबई और मद्रास के स्टुडियो आजकल धड़ाधड़ ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिनमें नायिका की मुख्य भूमिका है. और तो और, नायिकाओं को अब नायकों से भी ज्यादा कुछ करना पड़ता है. श्रीदेवी के मुताबिक पहले यह तय रहता था कि फिल्म में उनके कुछ नाच-गाने होंगे पर अब तो उन्हें मारधाड़ के भी कुछ दृश्य देने होते हैं. के.सी. बोकाड़िया की ताजा फिल्म (नाम अभी तय नहीं हुआ है) में वे अकेले ही खलनायक अनुपम खेर से भिड़ती हैं जबकि नायक जैकी श्रॉफ सिर्फ देखते रह जाते हैं.

'स्क्रीन' के संपादक उदय तारा नैयर कहते हैं, "इस नए दौर में अभिनेत्रियों को अभिनय के क्षेत्र में भी कुछ कर दिखाने का मौका मिला है. लेकिन सिर्फ रेखा जैसी सक्षम अभिनेत्रियां ही इन फिल्मों की जरूरतें पूरी कर सकती हैं." इस नई लहर से कैरियर में आए बदलाव का रेखा को भी एहसास है, "16 साल तक हिंदी फिल्मों में घिसी-पिटी भूमिका निभाते-निभाते मैं बोर हो गई थी

(ऊपर से) जेल की कोठरी से झांकतीं रेखा; मिथुन का साथ देतीं किम (बाएं) और मंदाकिनी; तथा छुरा लहरातीं हेमा: तेजी और तल्खी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और दो साल पहले तो मैंने इससे लगभग संन्यास ही ले लिया था. पर अब पहली बार एक अभिनेत्री के बतौर मैं संतुष्ट हूं."

टेक-4, सीन-46, फिल्म है दीपक मीरचंदानी की 'मदाम-एक्स'. बंबई के फिल्मीस्तान स्टुडियो में एक गंदी, बदबूदार जेल का सेट लगा है. दो हक्के-बक्के पुलिस सिपाहियों के बीच खूबसूरत मदाम-एक्स, यानी रेखा, चटकीले गुलाबी रंग के परिधान और पगड़ी में कुछ उग्र तेवर में खड़ी है. उसके हाथों में जालीदार काले दास्ताने, पैरों में काले जूते हैं. बड़ी शान से जब वह जेल में घुसती है तो पुलिस अफसर इस दुर्दांत अंतरराष्ट्रीय अपराधी को गिरफ्तार कर लेने की अपनी खुशी छिपा नहीं पाता. और कट्! और रेखा भी इस फिल्म में काम करने का अपना उत्साह छिपा नहीं पातीं. अपने कैरियर में दूसरी बार डबल रोल वे इस फिल्म में कर रही हैं. वे बड़े उत्साह से कहती हैं, "मदाम-एक्स एक ऐसा चरित्र है जिसे दुनिया पसंद करेगी. वह अपराध जगत की मलिका है. वह सोने की दीवानी है, वह उन्मादी है, एक सनकी चरित्र. मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो किसी हीरोइन ने अब तक न किया हो."

ज्यादातर अभिनेत्रियां वह सब कर रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था. मिसाल के लिए डिंपल ज्यादातर मारधाड़ वाले दृश्य खुद ही करना चाहती हैं. यही वजह है कि 'जख्मी औरत' में उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर किरण दत्त की भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाई है. हालांकि फिल्म में कुछ दृश्य इसकी विश्वसनीयता कम करते हैं. राज सिप्पी की फिल्म 'काली गंगा' में डिंपल ने डकैत की भूमिका निभाई है. इस तरह के एक्शन से काम में एक नया आयाम जुड़ गया है. श्रीदेवी कहती हैं, "यह वास्तव में बहुत थकाने वाला है. कभी-कभी दिन भर घोड़े पर शूटिंग करने के बाद अगली सुबह मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती."

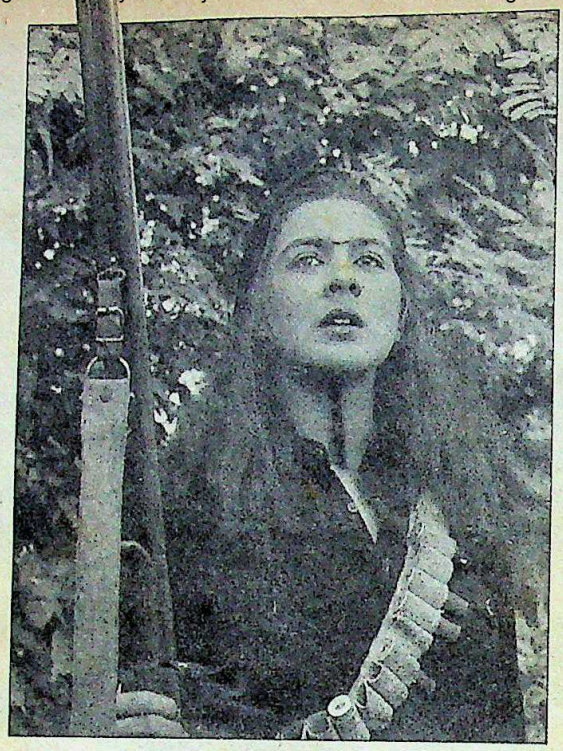

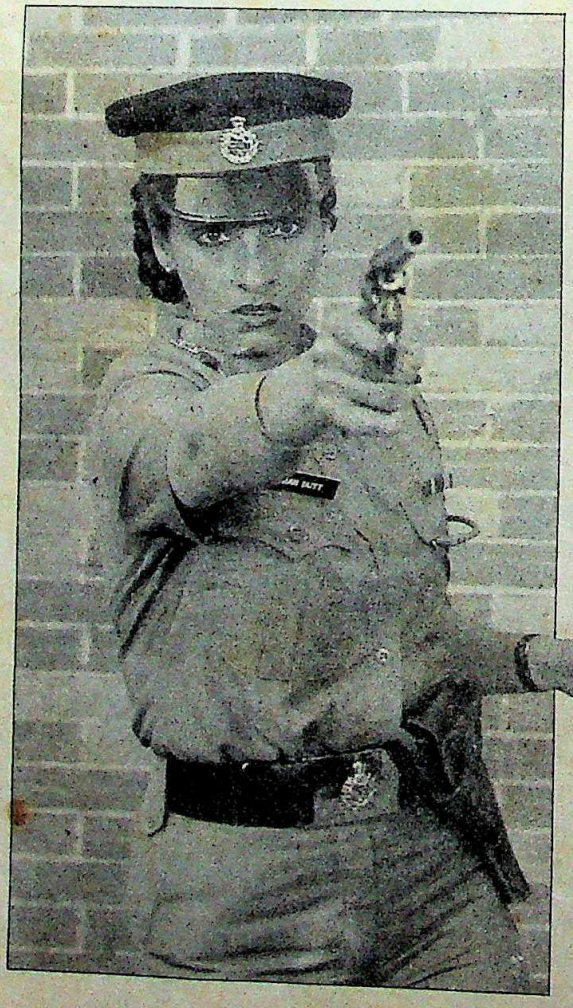

डाकू के भेष में अमृता (ऊपर); और पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में डिंपल: बदले की आग

'बॉबी' की सीधी-सादी मृग-नयनी लड़की की छवि वाली डिंपल के मन में अपने इस नए रूप के प्रति कुछ कड़वाहट है. वे कहती हैं, "जो चीजें अमिताभ बच्चन करते थे उन्हें करने में वाकई मजा है. पर अब वे आप से फाइटिंग करवाते हैं, नाच भी करवाते हैं, पर उतना पैसा नहीं देते जितना वे हीरो को देते हैं." फिर भी वे मानती हैं कि त्यागमयी, दुखी नायिका की भूमिका ज्यादा अरसे तक करते रहना मुमकिन नहीं है. दर्शक इस भूमिका को ज्यादा समय तक स्वीकार नहीं करेंगे.

हिंदी व्यावसायिक सिनेमा की स्वप्नसुंदरी कम और मानवीय दृष्टिकोण अधिक रखने वाली नायिका अब ज्यादातर छोटे परदे पर ही चली गई लगती है. वह दिवंगत स्मिता पाटील की 'वारिस' और हेमा की 'एक चादर मैली-सी' जैसी हाल ही की फिल्मों में भी कभी-कभार दिखाई देती है.

हिंदी व्यावसायिक सिनेमा के लिए यथार्थ से मेल खाना भी अब जरूरी नहीं रहा. मसलन हिंदी फिल्मों में महिला पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका कई बार फिल्माई गई, और ज्यादातर उसका नाम 'किरण' ही रखा गया. इनमें दिल्ली की विवादास्पद पुलिस अफसर किरण बेदी से मिलता नाम ही असलियत से मेल खाने वाली चीज थी. बेनेगल कहते हैं, "हिंदी सिनेमा से विश्वसनीयता के समीकरण पूरी तरह वस्तुतः गायब हो गए हैं."

लेकिन चाहे डिंपल रात भर अपनी यामाहा दौड़ाती रहें या श्रीदेवी घोड़े पर सवार होकर बीहड़ों की खाक छानती फिरें, यह सवाल अपनी जगह कायम है कि बार-बार इन गुस्सैल औरतों को पेश करके क्या दर्शकों को फुसलाए रखा जा सकता है? इस साल के आखिर तक जब बहुत सारी नारी प्रधान फिल्में प्रदर्शित होंगी, इस सवाल का साफ जवाब टिकट खिड़की पर ही मिल जाएगा.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाटक

रिश्तों की तीखी पड़ताल

व्यक्ति के प्रपंच, उधेड़बुन, नियति का सजीव चित्रण

पवन चतुर्वेदी की डायरी

नाटक

कुसुम कुमार

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली—110002.

कुल पृष्ठ—93, मूल्य 20 रुपए

अत्याधुनिक जीवन शैली का खोखलापन और पुरानी पीढ़ी के आदर्शों व मान-मर्यादाओं से वर्तमान यथार्थ की सीधी टकराहट आज के नाटक के मूलभूत विषय बनते जा रहे हैं. विजय तेंदुलकर और बादल सरकार की कृतियां इसके प्रमाण हैं. 'सारी रात', 'खामोश! अदालत जारी है' जैसे श्रेष्ठ नाटक और 'सात बज चुके हैं' जैसे 'टीवी नाटक' केवल मनोरंजन का 'प्रसाद' नहीं बांटते, रंगमंच से सबकी गहरी साझेदारी का भी एहसास कराते हैं. लेखिका कुसुम कुमार का नया नाटक—'पवन चतुर्वेदी की डायरी' भी पाठकों को उसी तनाव से गुजारता है.

लेखिका ने इस नाटक में मुख्य पात्र पवन चतुर्वेदी के माध्यम से पिता-पुत्र, पति-पत्नी-प्रेमिका, मां-बेटे के संबंधों की पड़ताल की है और अपनी इस प्रस्तुति में नाट्यानुशासन व प्रकाश योजना का भी पूरा ध्यान रखा है. लंबी अवधि (ड्यूरेशन) के इस नाटक में पवन चतुर्वेदी के संदर्भ में ही उसके पिता पद्मभूषण डॉ. चतुर्वेदी, उसकी पत्नी सुषमा और दो प्रोफेशनल व्यक्ति रूपों (मेहता व अग्निहोत्री) की भी मौजूदगी खास महत्व रखती है.

इस नाटक में एक व्यक्ति की कई-कई स्वीकारोक्तियों, नकार, उसकी उधेड़बुन और उसके शक्की मिजाज का हर प्रसंग में उद्घाटन होता है. यह व्यक्ति (पवन चतुर्वेदी) पिता की प्रतिष्ठा, पत्नी की खीझ-लताड़ और दोस्तों से खाए धोखे, यानी दुनिया भर से मिली नाकामयाबी के तजुर्बों की मार खाने के बाद एक लायब्रेरी की नौकरी में सिर छिपाकर लगभग कुंडली मारकर बैठ गया है. लेखिका ने केवल संवादों के जरिये ही अपने नाटक के सभी पात्रों की स्वभावगत कमजोरियों को पकड़ा है और मुख्य पात्र से उन सबकी डोर को भी बखूबी बांधे रखा है.

पूरे नाटक का तानाबाना पवन चतुर्वेदी के युवाकाल के सपनों, प्रेम विवाह, नौकरी, विवाह की असफलता और पिता के प्रभामंडल से मुक्ति की चाह को दर्शाता है. फ्लैश बैक का इस्तेमाल प्रसंग 'पति-पत्नी रामायण' में 'ए रेड लेटर डे' वाले अंश से कहीं ज्यादा कुशलता से किया गया है. लेकिन चार-चार प्रसंगों को फ्लैश बैक में दिखाना निर्देशक के लिए अवश्य ही आपद्धर्म रहा होगा. इससे बचा जा सकता था. कथ्य पर नाटककार की जो पकड़ है उसे रंगमंच की संयोजना के अनुकूल भी बनाया जा सकता था.

दक्षिण से दिल्ली आए मशहूर रंगकर्मी एस. सुब्बाराव का कथन ऐसे नाटककारों के लिए बड़े काम की चीज है. उन्होंने हिंदी नाटककारों के लिए एक 'लक्ष्मण रेखा खींची है, "ये हिंदी वाले रंगमंच की पृष्ठभूमि और उसकी सीमाओं को ध्यान में न रखकर केवल पाठकों के लिए नाटक लिखते हैं, दर्शकों के लिए नहीं. इन्हें चाहिए पहले वे रंगमंच के करीब जाएं और फिर अपनी तकनीकी प्रयोगशीलता को परखें."

कुसुम कुमार को भी अपनी प्रयोगशीलता और फ्लैश बैक तकनीक का ज्यादा सहारा नहीं लेना चाहिए था. लेकिन जीवंत संवाद और मुख्य पात्र को एकालाप की स्थिति से बचाए रखने की उनकी कामयाबी ही इस नाटक की सफलता है. नाटक के संवादों ने पिता-पुत्र के अंतर-बाह्य द्वंद्व और एक-दूसरे के प्रति असहमति व हताशा को उजागर किया है.

प्रेम विवाह के दस वर्षों में पत्नी से मिला चिड़चिड़ापन और गाली-गलौज (कलह) उसका 'हासिल' बनते हैं. दो बच्चों के बावजूद पत्नी उससे तलाक चाहती है. लेकिन पत्नी के संवादों के जरिये मुख्य पात्र के व्यक्तिगत जीवन का सही-विश्लेषण नहीं हो पाया, पिता का पात्र मुख्य पात्र की सही नब्ज टटोलता है (मगर अपने पूर्वाग्रह लादकर) मुख्य पात्र को उसका पिता उसकी जिंदगी का कुल जमा 'हासिल' एक ही वाक्य में समझा देता है कि "उसने उम्र से कुछ नहीं सीखा. तजुर्बों को अपना गुरु नहीं बनाया." लेकिन पिता का इस तरह कोंचते रहना भी उसे कुछ हासिल नहीं होने देता. पिता अपनी पसंद-नापसंद और बड़प्पन तक के बोझ से उसे दबाए रखना चाहते हैं. लेकिन वह जानता है—पिता का बड़प्पन उसे कुछ नहीं दे सकता, "पदवी या सिक्योरिटी भी नहीं." वह इसे और स्पष्ट करता है, "थोथी मानसिक एयाशी में मेरा विश्वास नहीं. आदमी को रोटी खाने को मिले...सुख-शांति, इमोशनल सिक्योरिटी...तो चाहे जहां पड़ा रहे चुपचाप!"

> **"मैं आदमी हूं! किसी और का चश्मा, किसी और का जूता... नहीं पहन सका... मैं अपनी जीभ अपने ही दांतों तले काटता हूं... मैं आदमी हूं... दूध का जला... छाछ का... आग का...."**
>
> 'पवन चतुर्वेदी की डायरी' से

यही पवन चतुर्वेदी की डायरी और उसके अंतरमन का सच है. वह जिंदगी को भी साजिश मानता है और अंतिम सच (मौत) को स्वीकार कर चुका है.

उसकी 'फेमिली सेंस' पर भी बाकी परिवार हमला करता है और वह पिता के 'पेसिमिज्म' को निशाना बनाता है. अंत तक एक प्रकार से वह अपने पिता की प्रतिछाया से लड़ता रहता है और उनकी शवयात्रा में (अपनी बड़बड़ाहट में ही) अपने जीवन का सत्य परिभाषित करता है—"मैं आदमी हूं! किसी और का चश्मा किसी और का जूता...नहीं पहन सका...मैं अपनी जीभ अपने ही दांतों तले काटता हूं...मैं आदमी हूं...दूध का जला... छाछ का...आग का...." पवन चतुर्वेदी की डायरी की परत दर परत इस तरह नाटक में खुलती चली गई है. लेकिन लेखिका को बेहिचक कलम चलाने से पहले पात्र की मानसिकता को गलीज होने से बचाने की चिंता करनी चाहिए थी. —प्रताप 'पारखी'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नीको®

इससे नहायेंगे तो त्वचा को सदा स्वस्थ पायेंगे.

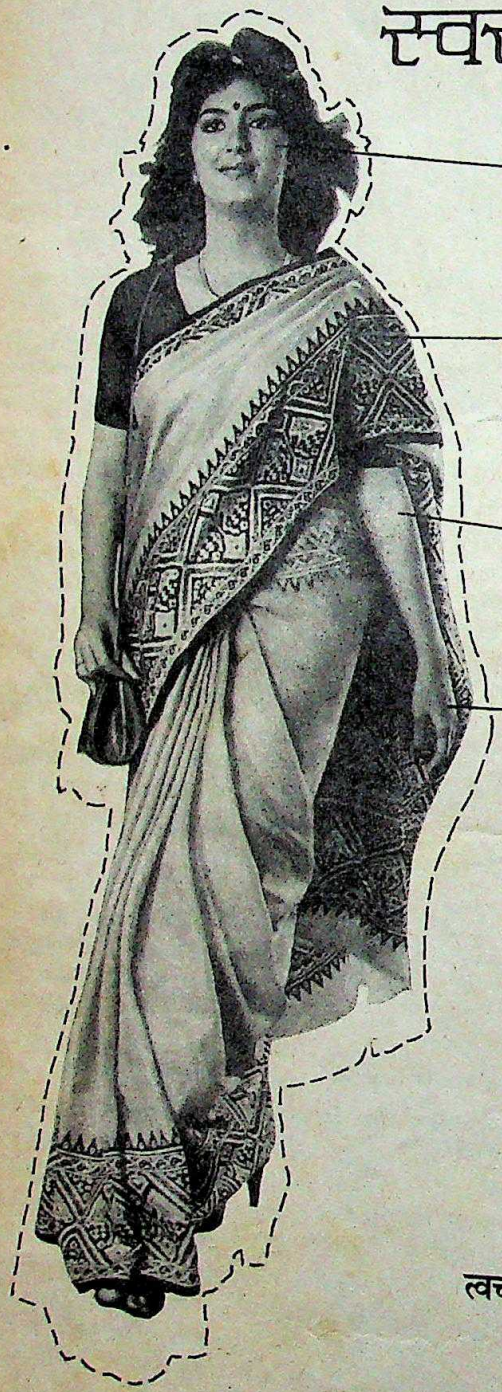

यह त्वचा की अतिरिक्त चिपचिपाहट को हटाता है जो मुहासों का कारण होती है.

यह शरीर की दुर्गंध मिटाता है, जिससे अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता है.

यह त्वचा पर से उन कीटाणुओं को हटाता है जो त्वचा को दूषित करते हैं.

यह त्वचा पर से धूल तथा उन तत्वों को हटाता है जो त्वचा रोग का कारण बनते हैं.

नीको साबुन आपके शरीर को पूर्णतया साफ करता है. यह शरीर की रक्षा भी करता है. क्योंकि नीको साबुन में होता है टी सी सी नामक तत्व जो बैक्टेरिया का जमकर मुकाबला करता है.

टी सी सी नहाने के पश्चात एक बहुत ही पतली व अदृश्य परत त्वचा पर जमाता है. यही परत त्वचा पर जमे बैक्टेरिया और शारीरिक दुर्गंध का डटकर घंटों मुकाबला करती है.

इसीलिए, नियमित रूप से नीको साबुन से नहाने पर आप दिन भर तरोताज़ा रहते हैं.

नीको® — औषधियुक्त त्वचा रक्षक साबुन

त्वचा की रक्षा पूरे दिन... हर दिन.

Parke-Davis (India) Limited, Saki Naka, Bombay 400 072.

® Regd. Trade Mark of Parke Davis & Company U.S.A., Licensed Users Parke Davis (India) Limited

PARKE-DAVIS

Contract-PD-45/88 Hn

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपन्यास

कथा नहीं, बहस का मुद्दा

शहरी सभ्यता के हमले से त्रस्त एक गांव की व्यथा कथा

थोकदार किसी की नहीं सुनता
उपन्यास
बटरोही
विभा प्रकाशन, इलाहाबाद
कुल पृष्ठ: 258, कीमत: 50 रु.

तलचट्टी—आजादी से पहले का—एक अनजाना पहाड़ी गांव, भारत के नक्शे में देखने पर अल्मोड़ा और चमोली के बीच कहीं एक बिंदु की तरह दिखेगा. मगर तब न तलचट्टी वालों को भारत का पता था और न भारत को तलचट्टी वालों का पता था.

यही तलचट्टी गांव दरअसल इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है जो एक भोले-भाले बालक के कलुआ थोकदार से हत्यारे कल्याण सिंह थोकदार बन जाने की व्यथा को मूक होकर झेलता है. कभी इस गांव के अपने विश्वास, अपनी आस्थाएं, अपने संस्कार और अपनी पैंच (वस्तु के रूप में लौटा देने के लिए लिया गया उधार) की अर्थ-व्यवस्था थी. "एक मुट्ठी नमक लेकर चाहे साल भर बाद दे, उसी मुट्ठी से भरकर नमक लौटाना होता था.....रुपया पैसा लोग जानते तो थे लेकिन आदान-प्रदान में वह कहीं भी बीच में नहीं आता था."

पहाड़ की चोटी पर उभरा हुआ एक काला शिलाखंड ध्यूल देवता के रूप में उनकी आस्था का आकाशदीप था, जो हमेशा गांव पर अपनी नजर रखता था. "मजाल कि कोई भी आदमी ध्यूल की नजरों से बच जाए."

कलुआ का बाप थोकदार दान सिंह जवानी में ही मर गया. इसलिए बालक कलुआ को थोकदार (किसी जमाने में राजस्व एकत्र करने वाला मुखिया जो सामान्यतः एक पट्टी का स्वामी होता था) की गद्दी संभालनी पड़ी. और अब बद्रीनाथ के यात्रियों के लिए चट्टी (सराय) तक खाने-पीने की सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की थी. जाने कब से चली आ रही थी यह निःस्वार्थ परंपरा. थोकदार यात्रियों के लिए आलू, टमाटर, नमक, गुड़ चट्टी में रख आता और यात्री अपनी मर्जी से वहां कुछ पैसे छोड़ जाते.

थोकदार का हलवाहा भंगीरुवा 'डुमौड़'. (असवर्ण जाति) है जिसमें रूपवती कुंतुलि ने जन्म लेकर बड़ी गलती की है. तभी तो भंगीरुवा गरियाता है उसे "वो तुझे लूट जाएं तो समझ तेरा भाग्य दाहिना हो गया और तुझे लूटलाट कर गधेरे में फेंक जाएं तो समझ ले तेरी मुक्ति हो गई....ये तेरी गोरी चमड़ी इस घर में क्या काम आनी है?" कुंतुलि जिसने पति के रूप में सिर्फ एक पीठ देखी थी, और चेहरा देखा था तो सभ्य समाज के एक ऐसे आदमी का जो अपनी सभ्यता उसके पेट में छोड़ जाता है. और उस पेट को छिपाने के लिए कुंतुलि एक दिन जाने कहां जंगल में गायब हो जाती है और फिर कभी लौटकर नहीं आती.

"लोग शहर जाने लगे और जब वापस आए तो....दूध की जगह चाय, हुक्का-चिलम की जगह कच्ची शराब आई... खेतों-नदियों के जिन किनारों में पहुंचकर हाथ मदद के लिए सहज ही सक्रिय हो जाते थे वे हाथ औरतों की ओर बढ़ने लगे"

'थोकदार किसी की नहीं सुनता' से

यहां बटरोही धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तलचट्टी को किसी कल्पना जगत का गांव नहीं बनने दिया. सामाजिक विषमता को वैसे का वैसा ही रहने दिया. उस पर किसी तरह के रोमांटिसिज्म को हावी नहीं होने दिया.

देश आजाद हुआ. पंचवर्षीय योजनाएं बनीं और उसकी आंच तलचट्टी भी पहुंची. शहरी सभ्यता को वहां तक पहुंचाने के लिए पनार नदी पर पुल बना. और यहीं से तलचट्टी की व्यथा की शुरुआत होती है. शहरी सभ्यता इसी पुल से होकर वहां पहुंचती है और पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती है. उनकी आस्थाएं बिजली की रोशनी में गायब हो जाती हैं. उसके विश्वास सरकारी पानी के बहाव में बह जाते हैं फिर "मोटर की तेजी की तरह ही ज्यादा से ज्यादा सुख-सुविधाओं को कम से कम वक्त में प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया.....लोग शहर जाने लगे और जब वापस आए तो अपने साथ नशीली आंखें लाए....दूध की जगह चाय, हुक्का-चिलम की जगह कच्ची शराब, बीड़ी की जगह सस्ती सिगरेटें और खेतों नदियों के जिन किनारों में पहुंचकर हाथ मदद के लिए सहज ही सक्रिय हो जाते थे वे हाथ औरतों और लड़कियों की ओर बढ़ने लगे."

नई मोटर संस्कृति ने लोगों का सौंदर्यबोध भी बदला और "सौंदर्य के जो मानदंड अभी तक गांव इलाके में तय होते थे, सीधे शहर से आयात किए जाने लगे." और इसकी परिणति हुई कभी एक बकरी की जान बचाने के लिए अचेत हो जाने वाले कलुआ थोकदार से हत्यारे कल्याण सिंह थोकदार बन जाने में.

उपन्यास में पंडित कपिलदेव पंत जैसे कामरेड भी हैं जो शहर में बैठे तलचट्टी जैसे गांवों के 'फोक कल्चर' की अपनी दुकान चलाते हैं. और जिनका मानना है कि "फोक लिटरेचर की स्टडी तो स्टेट्स में ही हो सकती है."....और "अंग्रेजी में जो कह दिया सारी दुनिया उसे मान लेती है और आखिर में तो हिंदी वालों को मानना ही पड़ता है." लेकिन यह चरित्र बड़ा नाटकीय लगता है और उपन्यास की मूल धारा से जुड़ नहीं पाता. कपिलदेव पंत की तरह ही उनके साथ के कुछ और चरित्र भी हैं जो बनावटी हो गए हैं.

उपन्यास में पहाड़ी गांवों के परिवेश के चित्रण में बटरोही बहुत सफल रहे हैं. बात-बात में वहां की स्थानीय बोली, भोली-भाली आस्थाएं और तर्कहीन विश्वास उस परिवेश को साकार कर देते हैं. लेकिन एक बात जरूर खटकती है कि एक प्रसंग जो पीछे छूट जाता है अचानक फिर आ जाता है. ऐसा जान-बूझकर किया गया है लेकिन इसमें भ्रम उत्पन्न होता है और प्रवाह भी रुकता है. 'थोकदार किसी की नहीं सुनता' से लगता है कि वह सामंती होगा लेकिन वह ऐसा कहीं नहीं लगता. दरअसल यह उपन्यास पाठक के मन में कथा नहीं बल्कि बहस का एक मुद्दा छोड़ जाता है.

—प्रकाश श्रीवास्तव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दुबई यात्रा

दिन लद गए

कस्टमवालों का कड़ा रुख

विदेश यात्रा पहले कभी इतनी आसान नहीं थी. हवाई जहाज का टिकट मुफ्त, वहां रहना मुफ्त और सबसे बढ़कर दुबई के विदेशी माल से अटे, आलीशान लेकिन भारत के मुकाबले सस्ते बाजारों में खरीदारी. ऊपर से इस तफरीह के बाद एक हजार रुपए का नकद इनाम भी.

हां, यह बात अलग है कि वहां खरीदे गए माल को इस सैर-सपाटे के आयोजकों यानी स्मगलरों के हवाले कर देना होता था. फिर भी सौदा बुरा नहीं था. सो लोग सैकड़ों की तादाद में दुबई का रुख करने लगे. लेकिन सहसा उपजे इस दुबई प्रेम से बंबई के सीमा शुल्क अधिकारी चौकन्ने हो उठे और उन्होंने ऐसे लोगों द्वारा साथ लाए सूटकेसों को खोलना शुरू कर दिया. उन्हें इन सूटकेसों में लाखों रुपयों की नाजायज चीजें मिलीं. आठ से पंद्रह मई के बीच ही लगभग एक करोड़ रु. का सामान पकड़ा गया. बंबई हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सीमा शुल्क अधिकारी ए.के. राहा कहते हैं, "पहले हर रोज 250-300 लोग तस्करी का सामान लाया करते थे, अब यह लगभग खत्म हो चला है."

दुबई के लिए निश्चय ही यह बुरी खबर है. खाड़ी युद्ध और तेल की गिरती कीमतों के कारण आई मंदी से उबरने के लिए अमीरात ने खाड़ी की इस पट्टी को एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं बनाई थीं. व्यापार के लिए आने वाले विदेशियों के लिए नियम उदार बनाए गए. उम्मीद थी कि इससे विदेशी माल खरीदने के लिए सिंगापुर जाने वाले भारतीयों को आकर्षित किया जा सकेगा.

यह योजना कामयाब भी होने लगी थी क्योंकि पिछले साल सिंगापुर ने भारतीयों के लिए वीसा अनिवार्य कर दिया था. खरीदारी के लिए आने वाले भारतीयों की मांग पूरी करने के लिए दुबई की गलियों के बाजारों में बड़ी संख्या में दुकानें खोली गईं. दुबई के भारतीय व्यवसायी और ट्रेवल एजेंट खरीदारी के लिए सस्ती दर पर दुबई की यात्राएं आयोजित करने लगे. नतीजतन पिछले साल भारत से दुबई जाने वाले यात्रियों की संख्या में 23 फीसदी बढ़ोतरी हुई. इस लाइन पर हर हफ्ते 19 उड़ानें भरने वाली एअर इंडिया के यात्रियों की संख्या में भी 170 फीसदी वृद्धि हुई.

लेकिन बंबई में की जा रही सख्ती के कारण यह योजना गड़बड़ाने लगी है. इस साल 50 फीसदी ज्यादा यात्रियों को ढोने का इंतजाम करने वाली हवाई सेवाएं उड़ानों के चार्ट दुबारा बनाने में लग गई हैं. खरीदारी के लिए आए पर्यटकों के बूते पर पनपते होटलों की आमदनी भी घट चली है. इस व्यापार के कुछ सांकेतिक शब्द भी प्रचलित हो गए थे. आर्डर पर तैयार किए गए सूटकेसों, जिन्हें ग्राहक अपने साथ ले जाते थे, को 'बंबई बॉक्स' कहा जाता था. रतन स्टोर चलाने वाले ईश्वर केशवानी बताते हैं कि ग्राहक खुद सामान छांटने की बजाय उन्हें ही पैसा थमा देते थे. "हम जानते हैं कि बंबई में किस चीज की मांग ज्यादा है. सो हम वे सभी चीजें बैग में भरकर उन्हें थमा देते थे."

'बंबई बॉक्स' हर आकार में मिलते हैं. सबसे सस्ते बक्से की कीमत 2,000 दिरहम (लगभग 7,000 रु.) है. ज्यादा जोखिम उठा सकने वाले खरीदारों के लिए जरा महंगा बक्सा 10,000 दिरहम (तकरीबन 35,000 रु.) का है. ओरके प्लाजा के प्रबंधक नरेंद्र कुमार सिंह बताते हैं, "कई बार तो हम अपने ग्राहकों को यह भी बता देते हैं कि भारत में अपना माल वे किस कीमत पर बेचें और खरीदारों के नाम भी सुझा देते हैं." अधिकांश खरीदार समूहों में आते हैं और उनके मुखिया के हाथ में खरीदे जाने वाले सामान की सूची होती है. वही सब की ओर से भुगतान करता है.

यात्रा आयोजित करने वालों का इंतजाम एकदम चुस्त-दुरुस्त रहता है. बंबई की कई ट्रेवल एजेंसियां दौरों की व्यवस्था करती हैं. मुफ्त की सैर करने वालों को 10-10 के समूह में भेजा जाता है क्योंकि समूह के टिकट सस्ते पड़ते हैं. दुबई के होटल तो पर्यटकों के लिए सात दिन के ट्रांजिट वीसा का भी इंतजाम करवा देते हैं.

दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा ट्रांजिट वीसा पर आए लोगों को अपनी सेवाएं देना बंद कर दिए जाने के कारण भी यह धंधा लगभग ठप पड़ गया है. लेकिन एक समस्या भी है. वह है—तस्करी का माल लाने वाले और जायज यात्रियों में अंतर कर पाने की. राहा कहते हैं, "हम पता लगाते हैं कि आने वाला व्यक्ति कितनी बार विदेश गया और वहां कितने दिन तक रुका. और यह भी कि यात्री जो चीजें ला रहा है, उन्हें खरीदने की क्षमता उसमें है भी या नहीं. यदि किसी के पास फिल्म के सौ रोल अथवा सौ साड़ियां है तो जरूर यह बेचने के लिए ही है."

तस्करों और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच चूहे-बिल्ली का यह खेल जारी है. लेकिन तस्करी के सामान के लिए मुफ्त विदेश यात्रा करने वालों के मौज-मस्ती के दिन लद चुके.

—इला निजर, दुबई में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कॉफ़ी की शान...

सर्वोत्तम 100% शुद्ध इन्स्टैंट कॉफी का शानदार स्वाद! खास चुने हुये कॉफी बीन्स से तैयार और भरपूर फ्लेवर-युक्त यह लाज़वाब कॉफी आप सब का दिल जीत लेगी।
आज ही गोल्ड कैफ़े लाइये और अपने परिवार के साथ आनन्द लीजिए। आप स्वयं कहेंगे "वाह! कॉफी का बेमिसाल अन्दाज़!"

GOLD CAFE

सर्वोत्तम 100% शुद्ध कॉफी

इन्सटंट कॉफी

कॉफ़ी का बेमिसाल अंदाज़!

CLARION D 885 HM

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजीव की विदेश यात्रा

कुछ लेकर आए, कुछ देकर

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विवादों की बारीक समझ का मौका

गोलन पहाड़ियों से जुड़ा सच जितना दुखदायी है उतना ही अतियथार्थवादी भी. सीरिया की चहलपहल भरी राजधानी दमिश्क से सड़क के रास्ते महज एक घंटे की दूरी पर स्थित यह इलाका एकदम प्राणहीन है. क्षितिज पर फैले शहर कुनीत्रा में अब कंकरीट के मलबे, मुड़ी-तुड़ी सलाखों और धराशायी हुए घरों का अंबार नजर आता है. उन गलियों में, जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब बारूद की बदौलत गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं.

यह ऐतिहासिक शहर एक जमाने में हराभरा था. लेकिन 1967 में इस्राएली सेना ने कुनीत्रा पर कब्जा जमा लिया और गोलन पहाड़ियां अरब-इस्राएली युद्ध की एक और दुखद याद बनकर रह गईं. 1974 में सीरियाई सेना ने फिर से कुनीत्रा पर अधिकार कर लिया. लेकिन जाने से पहले इस्राएली शहर की हर इमारत को ध्वस्त कर गए. तब से सीरिया ने इस शहर को ज्यों का त्यों सहेज रखा है.

पिछले पखवाड़े राजीव ने जिन चार देशों की यात्रा की सीरिया भी उनमें एक था. विश्व राजनीति में ऊंचा स्थान पाने को उत्सुक राजीव को जिस जोखिम भरे रास्ते से गुजरना है यह इलाका उसका एक प्रतीक है. सीरिया के ऐतिहासिक नगर दमिश्क में राष्ट्रपति हाफिज असद के साथ हुई मुलाकात राजीव के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अच्छा सबक साबित हुई. अरब-इस्राएल युद्ध शुरू होने के बाद युद्ध से जुड़े किसी अरब देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्री थी. असद के साथ हुई बातचीत ने राजीव को अरब राजनीति की जिस भूल-भुलैया के दर्शन कराए वह उनकी आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए. अरब राजनीति में असद की खासी भूमिका है. इसलिए यह यात्रा इस मायने में सफल रही कि राजीव को असद के साथ निजी घनिष्ठता बनाने का एक अच्छा अवसर मिला.

लेकिन इस भेंट के तीन दिन बाद ही न्यूयार्क में अपने होटल के कमरे में राजीव को तब अरब-इस्राएल टकराव से जुड़ी पेचीदगियों का एहसास हो गया जब अमेरिका के कुछ प्रमुख यहूदी नेताओं ने उनसे बातचीत की और इस्राएली सरकार के नजरिये से उन्हें परिचित कराया. हालांकि प्रधानमंत्री के साथ यात्रा पर गए अधिकारियों ने इस बैठक को चर्चा में आने से बचाने की कोशिश की पर प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना था कि भले ही यह मुलाकात उनके मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं थी पर

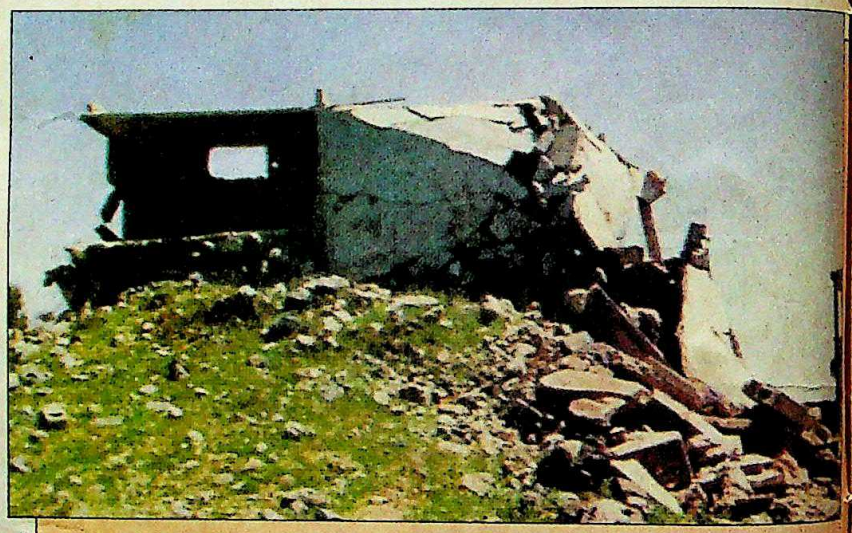

इस्राएली हमलों से बरबाद कुनीत्रा शहर ने राजीव गांधी को अरब-इस्राएल संघर्ष की कठोर सचाइयों का एहसास करा दिया

(बाएं ऊपर से नीचे) बरबाद कुनीत्रा शहर और सीरिया में पामीर के अवशेषों के सामने राजीव का दल; (दाएं ऊपर से नीचे) म्युनिच में कहकहे और बालटन में मोज

सभी फोटो: दिलीप भ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विचारों के इस आदान-प्रदान का राजीव ने भरपूर स्वागत किया है.

यह बैठक दरअसल वाशिंगटन में भारत समर्थक अमेरिकी सांसद स्टीफन सोलार्ज की कोशिशों का नतीजा थी. वे राजीव के साथ अपनी मुलाकात के समय इन यहूदी नेताओं को भी साथ लेते गए. बैठक के बाद अब साउथ ब्लॉक को निर्देश मिले हैं कि वह कुछ ऐसे रास्ते खोजे जिनसे अब तक ठप पड़े हुए भारत-इस्राएल कूटनीतिक संबंधों में कुछ सुधार तो हो पर अरब देशों के साथ भारत की दोस्ती पर भी कोई बुरा असर न पड़े.

पर पश्चिम जर्मनी का पड़ाव राजीव के लिए सबसे लाभदायक रहा. जर्मन उद्योगपतियों को भारत में पूंजी लगाने का निमंत्रण देने के अलावा राजीव को हेलमुट कोल जैसे अनुभवी नेता से पूर्व-पश्चिम विवाद की बारीकियों के बारे में जानने का मौका भी मिला. बल्कि कोल ने स्वयं पहल करते हुए राजीव से कहा, "आइए इस औपचारिक भोज को जल्दी से खत्म करें और फिर हम दोनों मेरे घर में अकेले में बातें करेंगे." जर्मन शिष्टाचार अधिकारियों के अनुसार यह एक असामान्य प्रस्ताव था.

प्रधानमंत्री के सहयोगियों के अनुसार कोल ने कई मामलों पर बातचीत की जिनमें निरस्त्रीकरण, पूर्व-पश्चिम रिश्ते, मास्को शिखर सम्मेलन और आगामी अमेरिकी चुनाव जैसे विषय भी शामिल थे. विदा होने से पहले कोल ने इच्छा जताई कि इस बातचीत को आगे जारी रखा जाना चाहिए. उन्होंने राजीव से कहा, "संपर्क बनाए रखिएगा. यूरोपीय मामलों पर जब भी आप हमारी तटस्थ राय जानना चाहें, हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं."

इस निमंत्रण से साऊथ ब्लॉक के अफसर बहुत खुश हैं. राजीव के एक सहायक का कहना था, "हम भी आस लगाए हुए हैं. प. जर्मनी इस समय यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हस्ती है और 1992 में जब यूरोपीय समुदाय एक साझा आर्थिक इकाई बन जाएगा तब वहां के आर्थिक और राजनैतिक मामलों में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी. राजीव की यात्रा के बाद यूरोपीय मंच पर हमें एक मजबूत दोस्त का साथ मिल गया है."

संयोग ही है कि कोल की अगली सरकारी यात्रा हंगरी की होने वाली है जहां राजीव न्यूयार्क जाते हुए रुके थे. बुडापेस्ट की यात्रा राजीव के लिए छुट्टी जैसी रही. हालांकि इसे सरकारी तौर पर 'सद्भावना यात्रा' का नाम दिया गया था पर यह इस मायने में महत्वपूर्ण रही कि इस दौरान उन्हें कैरोली ग्रोस के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने का अवसर मिला जो हाल ही में यानोस कादर के स्थान पर महासचिव बने हैं. भले ही इस बात का बहुत प्रचार नहीं हुआ पर प्रधानमंत्री बनने के बाद सोवियत संघ के अलावा किसी और कम्युनिस्ट देश की यह उनकी पहली यात्रा थी. डेन्यूब नदी के दोनों ओर बसा बुडापेस्ट शहर खासा खूबसूरत है और कम्युनिस्ट होने के बावजूद यह पश्चिमी यूरोप के शहरों जैसा लगता है. यहां के युवा और दूसरे अधिकांश लोग ताजा फैशन के कपड़े पहनते हैं. यहां के बाजार भी 'मैक्डोनल्ड' दुकानों समेत पश्चिमी तर्ज पर चलते दिखते हैं. यहां की सड़कों पर शराब के बार और नाइट-क्लब जहां-तहां देखे जा सकते हैं. लोग भी ज्यादा उन्मुक्त और दोस्ताना मिजाज के हैं.

शायद यही कारण था कि राजीव ने अपना अधिकांश समय सैर-सपाटे में बिताया. बालटन झील की सैर के दौरान प्रधानमंत्री ग्रोस ने सरकारी शिष्टाचार की परवाह न करते हुए खुद राजीव का साथ दिया और एक रेस्तरां में उनके साथ हंगेरियाई स्टाइल में पके परिंदों, मछली के सूप और आइसक्रीम का आनंद लिया. वहां से वे झील तक ड्राइविंग करते हुए गए जहां बिकनी में सजी हंगेरियाई सुंदरियों से घिरकर उन्होंने टैगोर मार्ग का उद्घाटन किया. इस यात्रा के महत्व के बारे में राजीव के एक सहयोगी का कहना था, "हंगरी छोटा-सा मगर कम्युनिस्ट खेमे का महत्वपूर्ण देश है. यह सामरिक महत्व के क्षेत्र में है (वियना यहां से नांव के रास्ते

लेकिन पश्चिम जर्मनी और हंगरी में गंभीर वार्ताओं के दौर चले तो कहकहों और सुंदर स्थानों के सैर-सपाटों के भी मौके मिले

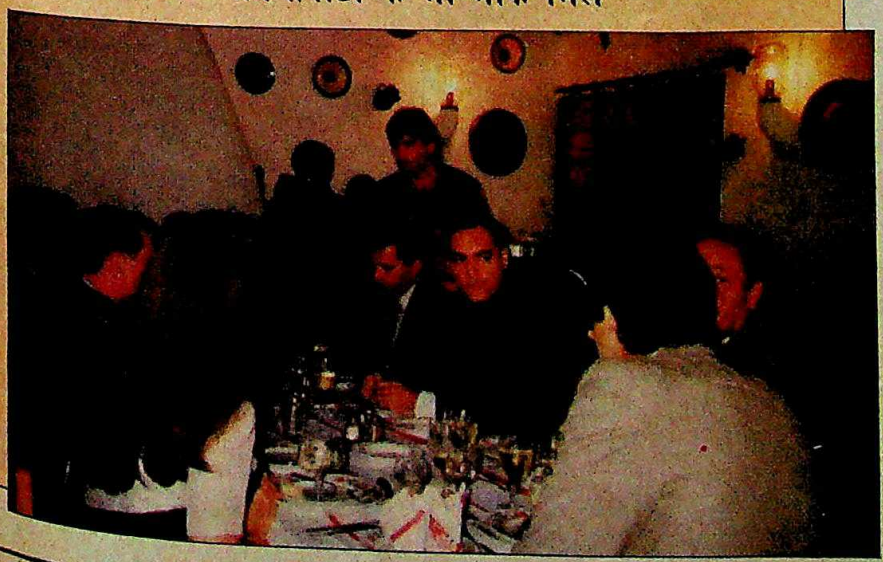

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Ar

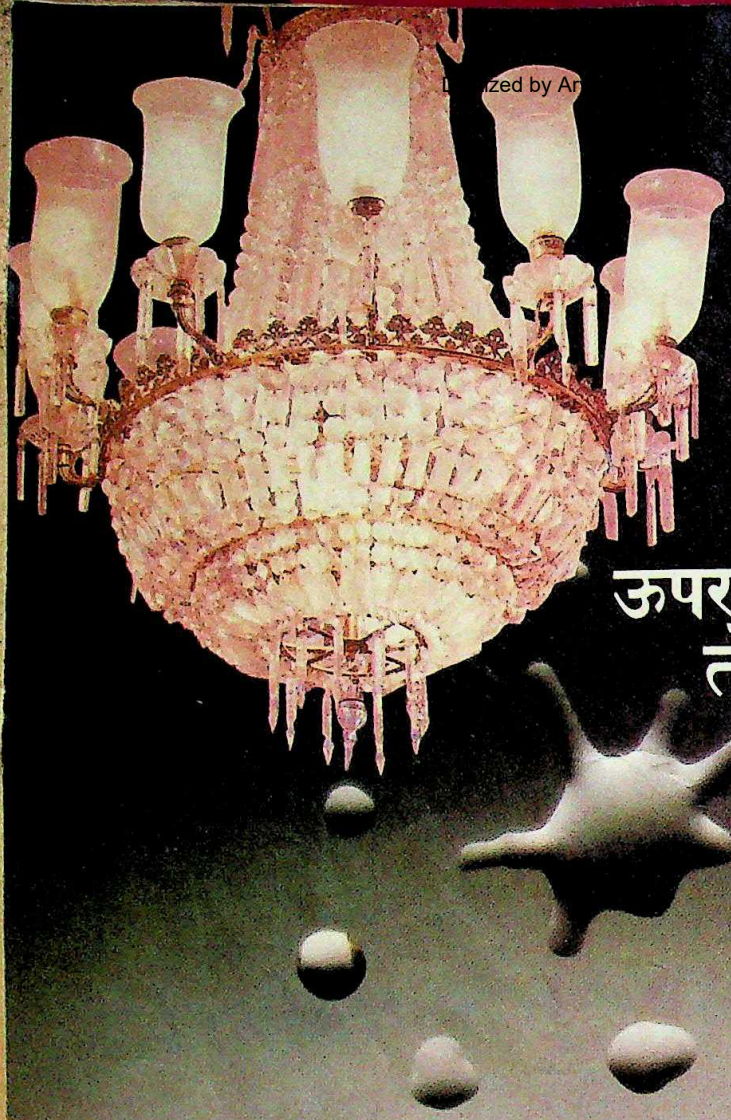

यूं तो सिन्हा दम्पति अपने १०,००० रुपए की कीमती झाड़-फानूस के बारे में काफ़ी सतर्क हैं...

लेकिन सिर्फ़ दो फ़ीट ऊपर ही, कहीं अनदेखा कर गये, तो सारी सजावट बर्बाद।

छत से पानी का रिसना।

जी हाँ! देखिए न! अधिकांश घर-मकानों में यह अनचाहा, लेकिन आम नज़ारा है। समय के साथ-साथ छत से पानी रिसने की त्रुटि किसी रोग की तरह बढ़ती जाती है और भयंकर साबित होती है। बरसात के मौसम के साथ हर बार आती है और न सिर्फ़ आपकी छत बर्बाद करती है, बल्कि घर में मौजूद कीमती सामानों को भी मटियामेट कर डालती है।

छतों की छिटपुट मरम्मत से भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ आपकी मेहनत की कमाई फ़िज़ूल बह जाती है।

इसीलिए, आपके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने घर को दें ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ सुरक्षा—एस. टी. पी. लिमिटेड की वॉटर-प्रूफिंग सुरक्षा।

हम...एस.टी.पी. के लोग छत से पानी रिसने की हर समस्या—चाहे घरेलू हो या कल-कारखानों की—दूर करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अपने इसी योग्यता के कारण पिछले ५० सालों से भी ज़्यादा, हम वॉटर-प्रूफिंग और क्षयकरण-विरोधी (कोरोशन-प्रोटेक्शन) कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे प्रभावशाली उत्पादनों में, समग्र सुरक्षा के लिए टारफ़ेल्ट और तत्काल वाटर-प्रूफिंग के लिए फ्लैशस्ट्रिप भी शामिल हैं। और एस.टी.पी. वॉटर प्रूफिंग का मतलब ही है—क्वालिटी की गारंटी।

इसीलिए आप जब भी अपना घर बनाएं और उसे अमूल्य सामानों से सजाएं तो इनकी स्थायी और भरपूर सुरक्षा के लिए, पहले थोड़ा-सा और खर्च करें। एस.टी.पी. वाटर-प्रूफिंग करा लें।

क्योंकि हम बखूबी जानते हैं, आपका घर आपकी अनमोल पूंजी है।

...और भयंकर संकटपूर्ण मौसम में भी एस.टी.पी. आपकी उस पूंजी को डूबने से बचा लेती है।

STP Limited

SHALIMAR TAR DIVISION

लीकेज के खिलाफ़ आपका सुरक्षा-कवच!

LINTAS (CAL) STP/44B/2720 HI

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केवल एक घंटे दूर है). इस कारण वे लोग दूसरे समाजवादी देशों के मुकाबले यूरोपीय मामलों पर ज्यादा जागरूक हैं और उन्हें अपने नजरिये से देखते हैं. यह एक अच्छा परिवर्तन है.'' इसके अलावा यात्रा के दौरान फायदे की कुछ और बातें भी हुईं. इनमें से रक्षा मामलों संबंधी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में हुआ समझौता भी है.

पर एक सवाल उठता है कि राजीव एक ही यात्रा में एक साथ कई देशों को शामिल क्यों करते हैं? नेहरू अपनी एक यात्रा में एक देश में ही 17 दिन तक लगा दिया करते थे और किसी देश में इंदिरा गांधी का पड़ाव औसत तीन दिन रहा करता था. लेकिन राजीव का अब तक का यह औसत प्रति देश केवल डेढ़ दिन है. भले ही वे ऐसी यात्राओं से अच्छा-खासा लाभ हासिल कर लेते हों पर यदि इन यात्राओं को कुछ लंबा रखा जाए तो शायद लाभ की मात्रा ज्यादा हो सकती है. वैसे भी 21वीं सदी आने में अभी तो काफी साल है. —दिलीप बॉब

राजीव के सहायक

अनूठी वफादारी

सरकारी दावतों और ऐसी ही दूसरी राजनयिक औपचारिकताओं के अलावा राजीव की यात्राएं अक्सर कम ही उबाऊ होती हैं. सीरिया में पामीर के प्राचीन रोमन खंडहरों से प्रेरणा पाकर प्रधानमंत्री के सहायकों ने खुद की तुलना प्रसिद्ध कॉमिक्स धारावाहिक 'एस्टेरिक्स' के पात्रों से करनी शुरू कर दी.

आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री के सहायक मोंटेक सिंह अहलूवालिया चूंकि हर वक्त तथ्यों और आंकड़ों की भाषा बोलते हैं, इसलिए उन्हें फौरन 'वाइटलस्टैटिस्टिक्स' (आंकड़ों के माहिर) नाम दिया गया. 'ओबेलिस्क' (स्तंभचिन्ह) की भूमिका में तो गोल-मटोल मणिशंकर अय्यर ही हो सकते थे. प्रधानमंत्री के नए प्रेस सहायक जी. पार्थसारथी ने तुरंत 'यूबिक्विटस' (सर्वव्यापी) की भूमिका स्वीकार कर ली. रोमन दंतकथाओं का यह सैनिक सर्वत्र घूमता है. उधर सरला ग्रेवाल को, जो 'ड्रेगन लेडी' की अपनी छवि के विपरीत वास्तव में ममतामयी महिला हैं, 'इंपेडिमेंटा' करार दिया गया. और 'एस्टेरिक्स' की भूमिका में प्रधानमंत्री के संकटमोचक गोपी अरोड़ा के सिवा और कौन हो सकता था?

ये तुलनाएं और भी आगे जाती हैं. यदि राजीव के भाषणों में हेनरिख हाइन, थॉमस मान और गेटे के उद्धरणों सहित अनेक लयात्मक प्रयोग होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कविता और साहित्य में उनकी अचानक रुचि पैदा हो गई है. इसका श्रेय अय्यर को ही जाता है. राजीव के भाषण जिस तरह से लिखे जाते हैं (वे एक साल में औसतन 250 भाषण देते हैं), उससे उनकी कार्यप्रणाली और अपने सहायकों पर उनकी निर्भरता का पता चलता है. किसी भी भाषण का पहला मसौदा अय्यर लिखते हैं और अगर उसमें आर्थिक पुट है तो बाकी योगदान अहलूवालिया का होता है. फिर अरोड़ा उसकी जांच करके अपनी टिप्पणियों या आपत्तियों सहित लौटा देते हैं. उसके बाद अय्यर की मर्जी हो तो वे अरोड़ा के सुझाव शामिल कर लेते हैं, या अगर जैसी कि उनकी आदत है, वे उनसे इत्तफाक नहीं रखते तो सीधे अंतिम निर्णय के लिए उसे राजीव के पास ले जाते हैं.

राजीव के उच्च तकनीक के प्रति प्रेम के कारण भाषण लेखन पहले से आसान हो गया है. अपने दफ्तर के कंप्यूटर पर महज एक बटन दबाकर अय्यर तत्काल कई आंकड़े और तथ्य जुटा सकते हैं. पर मुश्किल तो आगे आती है. न्यूयार्क में निरस्त्रीकरण पर दिया गया राजीव का भाषण इसकी मिसाल है. इसका मुख्य मसौदा अय्यर ने लिखा था जब प्रधानमंत्री अपने अमले के साथ एअर इंडिया के बोइंग 747 पर उड़ान के लिए पहुंचे और मसौदे पर विचार-विमर्श के लिए सभाकक्ष में इकट्ठे हुए तो अरोड़ा ने इस पर गंभीर आपत्तियां उठाईं.

राजीव के सहायकों के अनुसार प्रधानमंत्री विचार-विमर्श के दौरान तीन में से कोई एक तरीका अपनाते हैं. वे या तो बहस को नजरअंदाज करते हुए कागज पर कुछ लिखते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि दोनों पक्ष खुद ही किसी समझौते पर पहुंच जाएं. दूसरा तरीका यह है कि वे दोनों को बाहर जाकर सलाह-मशविरा करके संशोधित मसौदा तैयार कर लाने को कहते हैं. तीसरा और सबसे कारगर तरीका यह है कि वे किसी एक का पक्ष लेते हैं.

न्यूयार्क वाले भाषण के मामले में उन्होंने दूसरे नंबर का विकल्प चुना. अय्यर एक घंटे के लिए सभाकक्ष से बाहर गए. वहां अरोड़ा की आपत्तियों पर गौर करने पर उन्हें वे सही लगीं. फिर विमान के कंप्यूटर कक्ष में आकर (राजीव जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं उनके विमान में दो कंप्यूटर लगाए जाते हैं) उन्होंने संशोधित मसौदा तैयार किया. मामूली आपत्तियों के बाद अरोड़ा भी उस पर सहमत हो गए. फिर मसौदे को राजीव के कंप्यूटर पर भेज दिया गया.

लेकिन अमूमन अय्यर को लेकर होती बहस के बावजूद राजीव के सहायकों का बेहद महत्वपूर्ण गुण यह है कि वे अपने नेता के प्रति दीवानगी की हद तक वफादारी प्रदर्शित करते हैं. हालांकि निजी बातचीत में उनका लहजा कभी आलोचनात्मक भी होता है (जैसे कि ''वे बहुत से लोगों की सुनते हैं और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते''), पर नेता के प्रति अपने गजब के समर्पण भाव के कारण वे ऐसा जाहिर नहीं होने देते.

देश में तो उनकी खासी आलोचनाएं होती ही हैं पर विदेश यात्रा में राजीव के आकर्षण, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी प्रभावशाली भूमिका और सबसे बढ़कर उनकी अथक सक्रियता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता. आठ दिन की इस लंबी यात्रा में जहां उनके सहायक थककर चूर हो जाते, वहीं प्रधानमंत्री राजीव गांधी चंद घंटे नींद लेने के बाद ही बिस्तर से उठ बैठते और तरोताजा दिखते. —दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

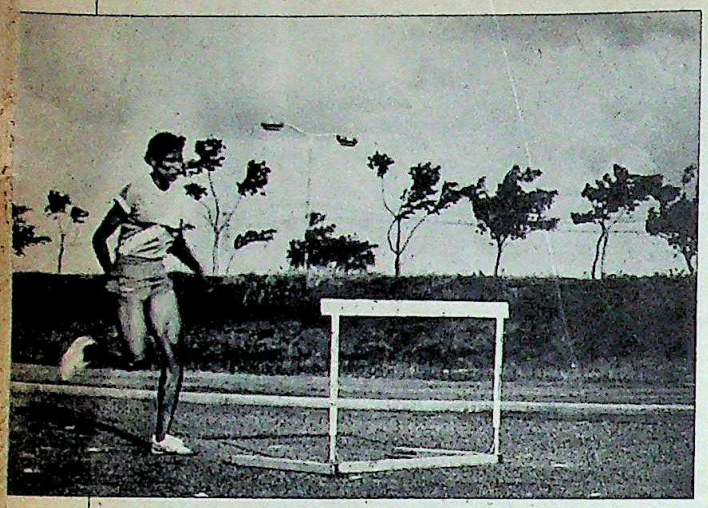

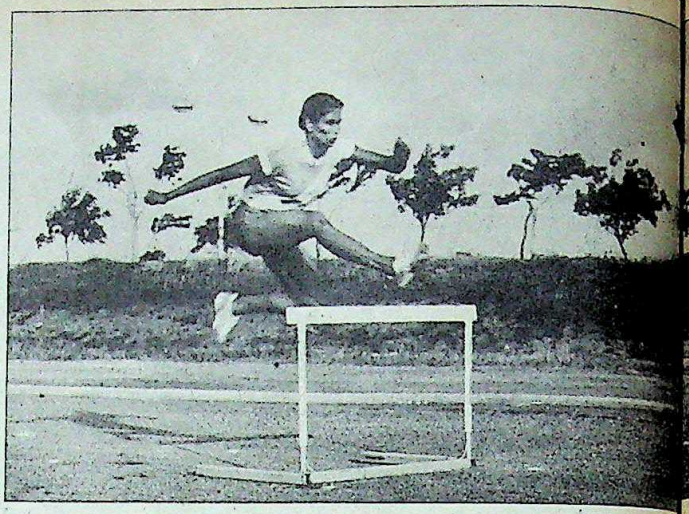

पी.टी. उषा

परों को तोलती उड़नपरी

सिओल ओलंपिक में पदक के लिए उषा की तैयारियां

केरल की यह 24 वर्षीया उड़नपरी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय धाविका है. और 400 मीटर बाधा दौड़ में तो एशिया में इसका कोई जोड़ नहीं है. बंगलूर में राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) के दक्षिणी केंद्र में इन दिनों बाधा दौड़ में महारत हासिल करने में लगी पी.टी. उषा के ख्वाबों की मंजिल अभी उनसे कुछ कदम दूर ही है. वह 400 मीटर बाधा दौड़ में ओलंपिक पदक जीतना चाहती हैं. लास एंजिलिस में चार साल पहले हुए ओलंपिक में वे 0.21 सेकेंड से पीछे रह गई थीं. सिओल ओलंपिक शुरू होने में केवल तीन महीने बाकी हैं (15 सितंबर से ये प्रतियोगिताएं शुरू होंगी) और उषा हफ्ते में छह दिन चार से पांच घंटे दौड़ती है. उनकी दिनचर्या इतनी सख्त है कि एनआईएस कैंप में ओलंपिक की तैयारी कर रहे दूसरे खिलाड़ी उनसे बात तक नहीं कर पाते.

भारतीय महिला एथलीटों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली यह लड़की 400 मीटर बाधा दौड़ में संयोगवश आई. 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों में जब इस दौड़ को पहली बार शामिल किया गया तो केरल की एक और धाविका एम.डी. वालसम्मा इसमें दौड़ने वाली थीं. खेलों की शुरुआत से पहले वालसम्मा ने विश्वास से कहा था, "मेरे और स्वर्ण पदक के बीच केवल 10 बाधाएं हैं." जब उन्होंने स्वर्णपदक जीता तो उनके प्रशिक्षक कृष्णन कुट्टी ने गर्व से कहा था, "यह भारत की उड़नपरी है."

लेकिन यह टिप्पणी शायद केवल एक शख्स को अखर गई. वह थे उषा के प्रशिक्षक माधवन नांबियार. उन्होंने 'कुट्टी को सबक सिखाने' का निश्चय किया और उषा को 400 मीटर बाधा दौड़ में उतार दिया. ओलंपिक से तीन महीने पहले उषा ने मई 1984 में ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वालसम्मा को पछाड़ दिया. चार और मुकाबले हुए और वे ओलंपिक फाइनल में पहुंच गईं. 55.42 सेकेंड का समय निकालने के बावजूद कांस्य पदक उनके गले में आते-आते रह गया.

ओलंपिक में उनके प्रदर्शन से उनकी ख्याति बढ़ गई. अब हालत यह है कि देश में धाविकाओं की वे सरताज हैं. 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है. एशिया में भी केवल 100 मीटर की दौड़ में उन्हें चुनौती देने वाली और स्वर्ण पदक विजेता फिलीपींस की लीडिया डी वेगा ही अकेली हैं.

खेल अधिकारियों, नांबियार और खुद उषा ने केवल एक तरह की दौड़ पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत महसूस नहीं की है, जबकि संसार के दूसरे श्रेष्ठ एथलीट ऐसा करते हैं. मुकाबले की अदम्य इच्छा की वजह से उषा बहुत सारी दौड़ प्रतियोगिताओं मे हिस्सा ले रही हैं ताकि ढेरों स्वर्ण पदक जीत सकें. प्रशासनिक अधिकारी इसलिए खुश हैं क्योंकि उनकी 'लागत का प्रतिफल' काफी फायदेमंद साबित होता रहा है. दूसरी ओर कुट्टी को नांबियार यह दिखाना चाहते हैं कि असली 'उड़नपरी' उनके पास है.

लेकिन जब यह भारतीय उड़नपरी सिओल में उतरेगी तो उसे बहुतेरी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा. 35-35 मीटर की दूरी पर 30-30 इंच ऊंची (महिलाओं के लिए) 10 बाधाओं को उसे पार करना होगा. और आखिरी बाधा दौड़ समाप्ति रेखा से 45 मीटर पहले होगी. 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए चौथाई मील दोड़ने वाले जैसी गति, आधा मील दौड़ने वाले जैसी ताकत और ऊंची बाधा वाले धावक की तकनीक की जरूरत होती है. विश्वस्तर के बाधा धावक अमूमन 40 बाधाएं समान-समान 15 लंबे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: श्रीनिवास कुमार

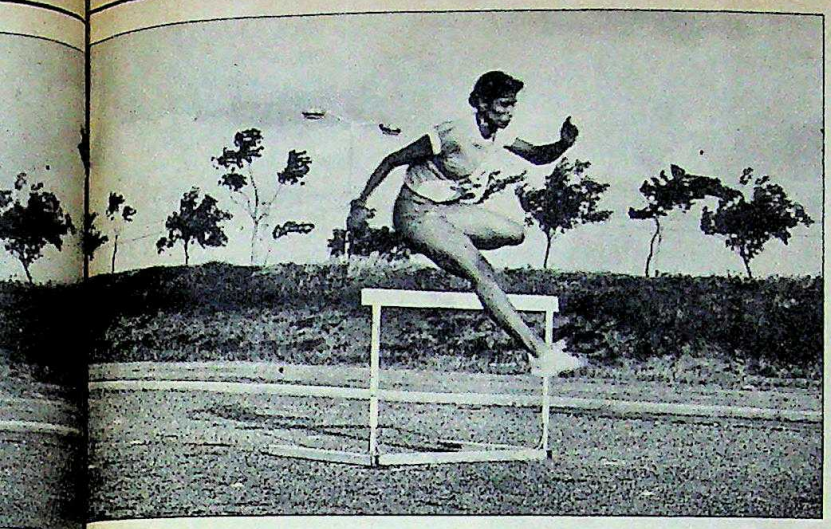

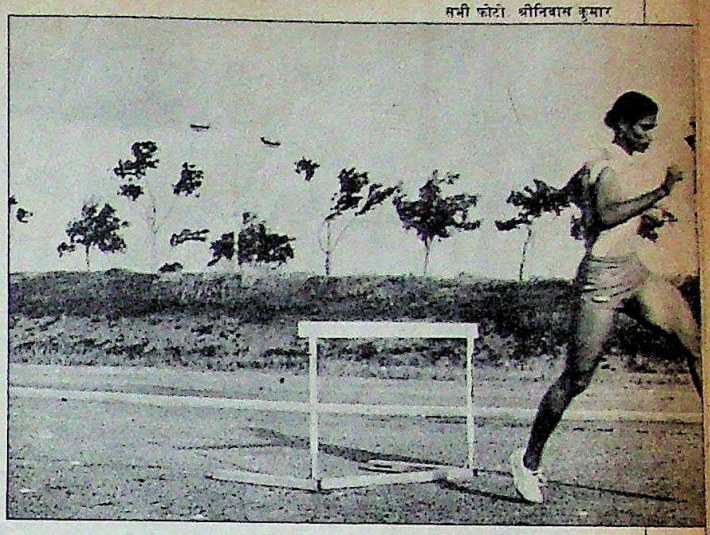

डग भरकर पार कर लेते हैं.

उषा अफसोस जाहिर करते हुए कहती हैं, "लास एंजिलिस में मैंने बाधाएं 17-17 डग भरकर पार की थी." थोड़े मगर लंबे डगों से वक्त और शक्ति दोनों की बचत होती है.

पांच फुट सात इंच लंबी उषा की टांगें ज्यादातर यूरोपीय एथलीटों की तरह ही बेहद लंबी हैं जिससे बाधा पार करना आसान हो जाता है. सहज डग भरने का तरीका और शक्तिशाली मांसपेशियां उनकी गति में इजाफा करती हैं. लेकिन वे स्वीकार करती हैं, "अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में जीत हासिल करने के लिए केवल इतना हीं काफी नहीं है."

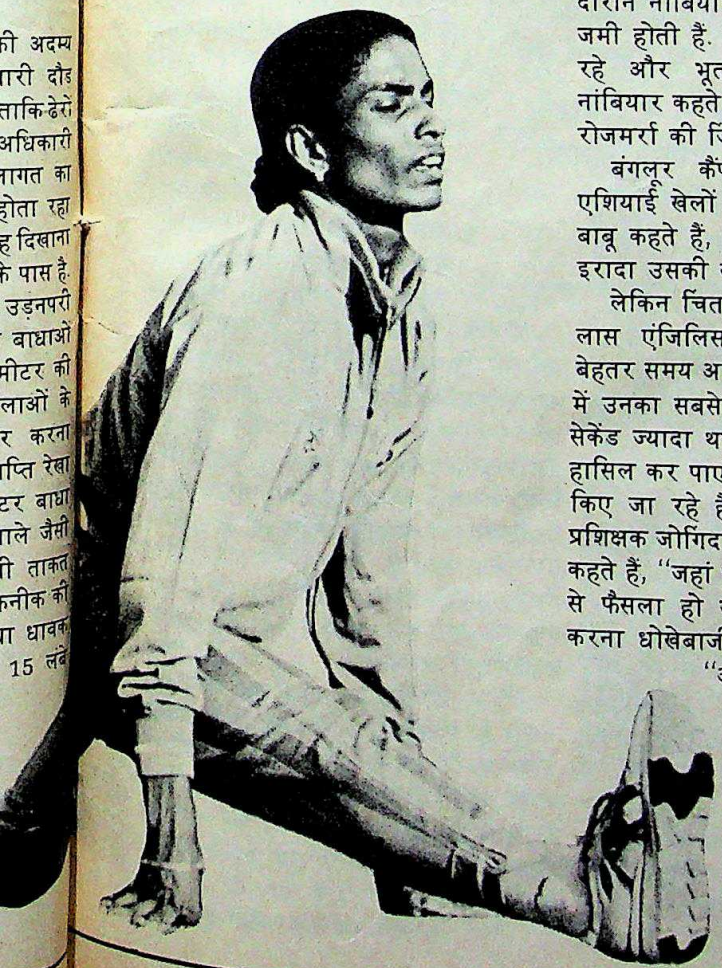

एनआईएस के ट्रैक पर वे चार से पांच घंटे तक अभ्यास करती हैं. और इस दौरान नांबियार की पारखी निगाहें उन पर जमी होती हैं. उषा के 10 वर्षों से प्रशिक्षक रहे और भूतपूर्व वायुसैनिक 55 वर्षीय नांबियार कहते हैं, "नियमित अभ्यास उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है."

बंगलूर कैंप के इंचार्ज और बैंकाक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सुरेश बाबू कहते हैं, "दृढ़ इच्छाशक्ति और पक्का इरादा उसकी खासियत है."

लेकिन चिंता की बात यह है कि उषा ने लास एंजिलिस मुकाबलों के बाद उससे बेहतर समय अभी तक नहीं निकाला है. रोम में उनका सबसे बेहतर समय भी उससे 21 सेकेंड ज्यादा था. सिओल में वे कोई तमगा हासिल कर पाएंगी इस संबंध में संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं. मुख्य राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह सैनी चेतावनी देते हुए कहते हैं, "जहां कुछेक माइक्रो सेकेंड के अंतर से फैसला हो जाता हो वहां भविष्यवाणी करना धोखेबाजी है." सुरेश बाबू कहते हैं, "ओलंपिक के बाद उसने कोई करिश्मा नहीं दिखाया है. यही वजह है कि उससे सिओल में कुछ कर दिखाने की उम्मीद की जा रही है."

बंगलूर में अभ्यास करने के बाद उषा त्रिवेंद्रम में एक पखवाड़े तक सिंथेटिक सतह पर प्रशिक्षण लेंगी. फिर वे इंग्लैंड, इटली और हंगरी में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक पांच प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी.

इस सबके अलावा उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी होगी. ये हैं रोम विश्वकप में 53.62 सेकेंड में दौड़ पूरी करने वाली पूर्व जर्मनी की सेबाइन बुश, पूर्व जर्मनी की एक और धाविका कोर्नेलिआ उलरिच, ऑस्ट्रेलिया की डेब्बी फिलिटोफ किंग, जमैका की सांड्रा फार्मर, फिनलैंड की टुइजा हेलांडर और रूस की अन्ना एंब्राजेन. ये सभी 53 से 54 सेकेंड के बीच दौड़ पूरी कर लेती हैं. जबकि उषा इससे कहीं ज्यादा 55.42 सेकेंड लेती हैं.

इस बीच उषा ने अपनी तकनीक को सुधारा है. उन्होंने अपनी दौड़ की शुरुआत में सुधार किया है. वह शुरुआत का पहला कदम अधूरा रख पाती थीं जिससे शुरुआत में पूरी ताकत से वह नहीं दौड़ पाती थीं.

अपने एथलीट साथियों के लिए उषा अभी भी कभी-कभार बातचीत करने वाली साथी हैं. एशियाई ट्रैक ऐंड फील्ड चैंपियनशिप की 400 मीटर की दौड़ में उषा के थोड़ा पीछे रहने वाली और रजत पदक विजेता वंदना शानबाग कहती हैं, "पिछले दो महीनों के दौरान मैं एक बार भी उसके कमरे में नहीं गई." एनआईएस केंद्र के निदेशक ए.एस.वी. प्रसाद कहते हैं, "उसे अपने लक्ष्य से कोई विचलित नहीं कर सकता. और वह देश भर की उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देगी."

कुछ ही महीनों बाद जब सिओल में ओलंपिक शुरू होंगे तो जाहिर है कि उषा से उम्मीदें बेहिसाब होंगी. और उड़नपरी के लिए एक ओलंपिक पदक जीत लाने का भी यह आखिरी मौका ही होगा.

—अमरनाथ के. मेनन, बंगलूर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय हॉकी

आखिर कुफ्र टूटा

नैरोबी में जीत से हौसला बढ़ा

बी. जॉन/द हिंदू

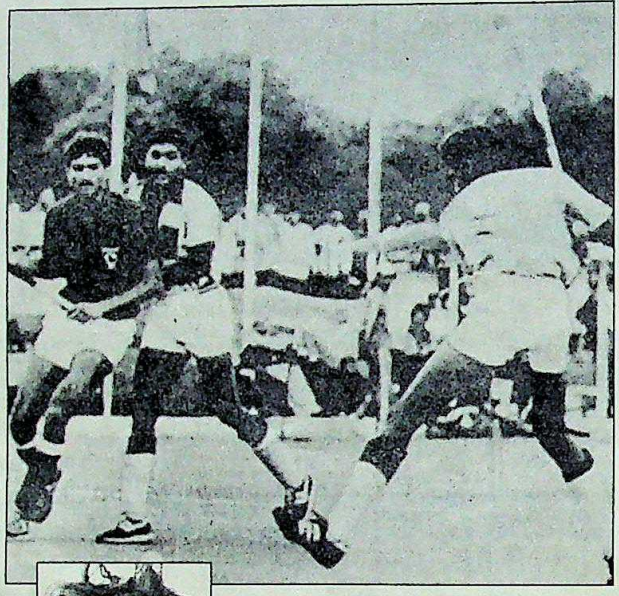

बलविंदर (दाएं) की आक्रामक मुद्रा

नैरोबी में जीत से मनोबल तो बढ़ा है लेकिन असली परीक्षा तो सिओल ओलंपिक में होगी

पैटर्सन

तीस महीनों से तपती धरती को जैसे बारिश की फुहारों ने सकून पहुंचा दिया. पिछले दिनों नैरोबी में हुए मार्शल्स इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की विजय ने कुछ ऐसी ही सुखद अनुभूति कराई. इस जीत में उल्लेखनीय बात यह है कि भारत ने अपने परंपरागत विरोधी पाकिस्तान को लीग और फाइनल मैच में भी शानदार तरीके से हराया. सिओल ओलंपिक के करीब तीन महीने पहले इस जीत से भारतीय टीम और उसके प्रशिक्षक को कम-से-कम यह तो भरोसा हो ही जाना चाहिए कि भारतीय हॉकी के पतन को रोकना संभव है. टीम के कप्तान एम.एम. सोमैया ने कहा, "जीतना अच्छा लगा. यह तो ओलंपिक की तैयारी भर है."

लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज करना मुश्किल है कि नैरोबी में हॉलैंड, आस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी, इंग्लैंड और दक्षिण कोरिया जैसी दिग्गज टीमें मौजूद नहीं थीं. लेकिन पाकिस्तान पर जीत हमेशा संजीवनी की तरह ही काम करती है. 70 के दशक में भारतीय हॉकी टीम के तेजतर्रार फारवर्ड माने जाने वाले एम.पी. गणेश ने कहा, "ओलंपिक के पहले इस जीत से भारतीय टीम का मनोबल बढ़ेगा. उसमें नई जान आएगी."

लेकिन इस जीत से जो सबसे अहम तथ्य उजागर हुआ वह यह है कि हॉकी की भारतीय शैली अभी भी अपना कमाल दिखा सकती है. लगभग एक दशक तक यूरोपीय शैली में पारंगत होने की असफल कोशिशों के बाद पहली दफा भारत ने इस टूर्नामेंट में 5-3-2-1 की शैली में आक्रामक खेल खेला. लंबे समय के बाद इस दफा खिलाड़ी टीम भावना से खेले और खेल के कुछ बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिले. गोलकीपर मार्क पैटर्सन निश्चित तौर पर हीरो बन कर उभरे. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में इस नए खिलाड़ी ने कई बेहतरीन पेनाल्टी शॉट बचाए. बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दूसरे खिलाड़ियों में थोइबा सिंह और बलविंदर सिंह रहे. थोइबा सिंह को सबसे खतरनाक लेफ्ट विंगर माना जाता है. सोमैया उन्हें 'बिजली' कहा करते हैं. सेंटर फारवर्ड बलविंदर सिंह ने टूर्नामेंट में नौ गोल दागे. इसके अलावा फुल बैक परगट सिंह और अशोक कुमार ने क्षेत्ररक्षण का शानदार खेल दिखाया.

गोल दागने की अक्षमता हमारे खिलाड़ियों की बड़ी कमजोरी रही है. नैरोबी टूर्नामेंट में भी यह कमजोरी कई बार आड़े आई. पेनाल्टी कार्नरों को गोल में तब्दील करने में वे कई बार नाकाम रहे. 24 पेनाल्टी कार्नरों में से सिर्फ दो ही गोल में बदल पाए. भारत के प्रशिक्षकों और वरिष्ठ खिलाड़ियों का कहना है कि हमारे गोलंदाज इस महत्वपूर्ण कला में विशेषता हासिल करने के प्रति उदासीन हैं.

और जहां तक मैदानी गोलों का सवाल है, बलविंदर की तेजी के आगे यह नहीं भुला देना चाहिए कि अभी भी भारत की अग्रिम पंक्ति में विश्व के कुछ सबसे बढ़िया ड्रिब्लर हैं. नैरोबी में भारतीय टीम ने जो 19 गोल किए उनमें 13 मैदानी गोल फारवर्डों ने बनाए. लेकिन दमखम में बीस यूरोपीय टीमों के खिलाफ मैदानी गोल दागना सचमुच मुश्किल होगा.

बहरहाल, विडंबना यह है कि भारतीय टीम को अपने इस नए कौशल को किसी यूरोपीय या आस्ट्रेलियाई टीम पर आजमाने का ओलंपिक के पहले कोई मौका नहीं मिलेगा. लेकिन भारतीय टीम के प्रशिक्षक गणेश की नजर 26 जुलाई से पाकिस्तान के साथ शुरू होने वाली छह मैचों की श्रृंखला पर है. वे सिओल ओलंपिक के लिए अब तक की तैयारी से खुश नहीं हैं, "सिर्फ ढाई महीने की तैयारी से कोई तगड़ी टीम कैसे बन सकती है? ओलंपिक के लिए हमें साल भर पहले से तैयारी करनी चाहिए थी." पूरी टीम की शारीरिक क्षमता और मनोबल को भरपूर बढ़ाने की हर संभव कोशिश चल रही है. खिलाड़ियों में ज्यादा दमखम और फुर्ती लाने के लिए दवाइयों का भी प्रयोग किया जा रहा है. पहली दफा भारतीय टीम के प्रशिक्षण दल में एक मनोचिकित्सक भी शामिल किया गया है. टीम को खेल की तकनीक का प्रशिक्षण गणेश और गोविंदा दे रहे हैं.

मौजूदा भारतीय टीम में नए और अनुभवी खिलाड़ी दोनों ही हैं. नए-पुरानों का अनुपात भी ठीक है. गणेश का दावा है कि इस टीम का प्रदर्शन देखने लायक होगा. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने नए खिलाड़ियों के भरोसे ही सब कुछ दांव पर लगाया है. सिओल में भारतीय टीम की संभावना पर गणेश कहते हैं, "सेमीफाइनल में हमारे लिए पहुंचना भी एक उपलब्धि ही होगी. एक बार सेमी फाइनल में पहुंच जाने पर तो कुछ भी हो सकता है."

लेकिन यह निराशा का पुराना राग ही लगता है. सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए और अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए भारतीय हॉकी को अपने पुराने जादू और आत्मविश्वास को जगाना होगा. क्या यह संभव हो पाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल यही है.

—एम. शंकर और महेश कृष्णमूर्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कलकत्ता

जिहादी पर जुल्म

ब्रिटिश डॉक्टर पर दबाव

कलकत्ता के मिड्लटन रो इलाके की फुटपाथ पर फटे-चिटे तिरपाल के नीचे हर रोज हजारों की भीड़ लगती है. इस तंबू के नीचे सुबह नौ बजे से दोपहर बाद तक 57 वर्षीय डॉक्टर जैक प्रेगर रोगियों का मुफ्त परीक्षण करते हैं. मुफ्त दवाइयां देते हैं. तभी तो सभी रोगी उन्हें अपना मसीहा मानते हैं. लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों ने प्रेगर को देश से बाहर निकालने की ठान ली है. प्रेगर कहते हैं, "वे मुझे मेरी आत्मा से अलग करना चाहते हैं."

उनका 'फुटपाथ क्लिनिक' लगाने सबसे पहले आते हैं एम.डी. सफवी जो पहले प्रेगर के मरीज थे और अब उनकी क्लिनिक के एक कर्मचारी. वे तिरपाल तानते हैं और पानी भरकर रखते हैं. दूसरे कर्मचारी हैं खुशमिजाज देवानंद जिनकी टांगें पोलियो-ग्रस्त हैं. वे दवाइयां बांटने के लिए रद्दी कागज से छोटे-छोटे लिफाफे बनाते हैं. वे कहते हैं, "डॉक्टर हमारे भगवान हैं. उन्होंने ही मुझे यह हाथ रिक्शा दिया है."

ब्रिटेन के पासपोर्टधारी प्रेगर इन दिनों उन सरकारी विभागों से जूझ रहे हैं जो उन्हें इस देश से बाहर निकाल देने की ठाने हुए हैं. वे कहते हैं, "मैं स्थायी आवासीय परमिट हासिल करने की जद्दोजहद में हूं और वे पिछले आठ वर्षों से मुझे इसे देने से इनकार करते आ रहे हैं. लेकिन मेरी कोशिशें अभी जारी हैं." उन्होंने 'आखिरी सांस तक लड़ने' की ठान ली है. और वे मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने अथवा राष्ट्रपति से अपील करने तक का इरादा रखते हैं.

उन्होंने आयरलैंड गणराज्य के फिजीशियन ऐंड सर्जन कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की. 1972 में वे इंटर्नशिप पूरी करने वाले थे. उन्हीं दिनों आयरिश रेडियो ने बांग्लादेशी शरणार्थियों के बीच काम करने के इच्छुक स्वयंसेवकों की भर्ती की अपील जारी की. प्रेगर कहते हैं, "मैंने तुरंत आवेदन किया और 'कन्सर्न' नामक एक आयरिश सामाजिक संगठन से संबद्ध होकर पूरब चला आया." उन्होंने सईदपुर शरणार्थी शिविर में काम किया और दो

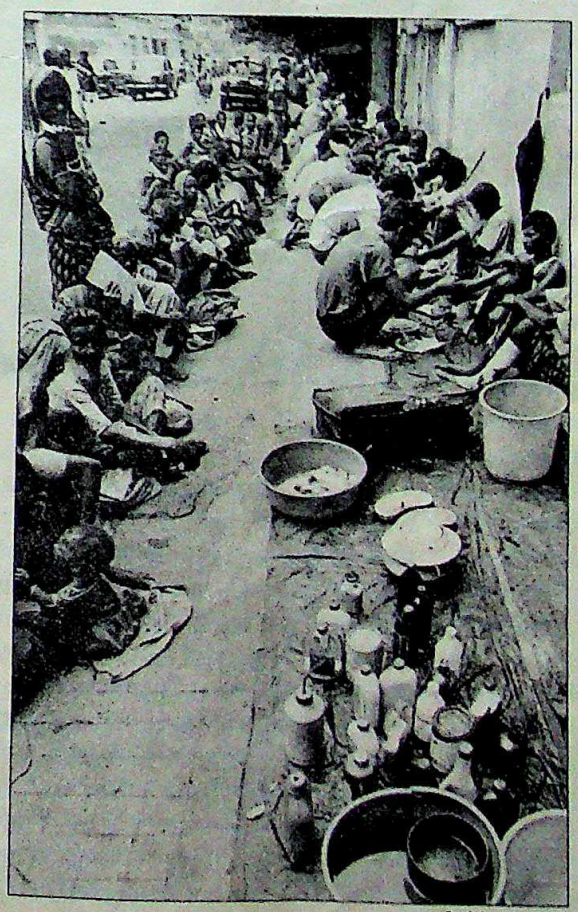

एक रोगी के साथ प्रेगर और (बाएं) उनका फुटपाथ क्लिनिक

साल बाद 'टेरे डेस होम्स' नामक एक डच संगठन से संबद्ध होकर वे ढाका आ गए.

इस दौरान प्रेगर के पास शिकायतें आने लगीं कि 'टेरे डेस होम्स' फर्जी अभिभावकों के जरिये बांग्लादेशी बच्चों को अवैध तरीके से बाहर भेज रहा है. जब उन्होंने इस मसले को संगठन के सामने उठाने का फैसला किया तो बांग्लादेश के अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी. फरवरी 1979 में उन्हें बैंकॉक जाने वाले विमान में बैठा दिया गया. किसी तरह वे अपने देश पहुंच गए.

लेकिन 'बंगभाषियों' के प्रति उनके स्नेह ने उन्हें वापस आने को मजबूर कर दिया. बांग्लादेश में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध होने की वजह से वे अगस्त 1979 में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कलकत्ता आ गए बांग्लादेशी शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए. कलकत्ता में एक बार प्रेगर ने मदर टेरेसा के संगठन के तहत काम करना शुरू किया.

इस बीच प्रेगर ने स्थायी आवास परमिट के लिए राज्य सचिवालय रायटर्स बिल्डिंग के बार-बार चक्कर लगाए. लेकिन उन्हें यह परमिट हासिल नहीं हुआ. जून 1980 में उन्हें तीन महीने के लिए रहने की अनुमति दी गई. और सितंबर 1980 में केंद्र सरकार ने उनके निष्कासन के आदेश जारी कर दिए. प्रेगर भागे-भागे दिल्ली गए और इस आदेश को स्थगित करवाया. लेकिन जून 1981 में निष्कासन का दूसरा आदेश जारी कर दिया गया— इस बार राज्य सरकार की ओर से. और फिर 1982 में उन पर पासपोर्ट पर उचित अनुमोदन के बिना भारत में दाखिल होने और देश छोड़कर जाने के केंद्र सरकार के आदेश का उल्लंघन करने के लिए विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत दोषी ठहराया गया. उन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया. आठ दिनों बाद उनके एक मित्र ने उन्हें जमानत पर छुड़ाया. उसके बाद से उन पर लगातार नजर रखी जा रही है.

यह जिहादी डॉक्टर झोंपड़पट्टियों में लाचारों की सेवा में जुटा है. लेकिन 1983 में जब सर्कुलर रेल योजना पर काम शुरू हुआ तो कई झोंपड़पट्टियां साफ कर दी गईं. अब प्रेगर के लिए एक निश्चित स्थान पर बैठकर रोगियों को देखने का ही रास्ता बच गया. और उन्होंने सेंट थॉमस प्रेस्बिटरी गिरजाघर के बाहर फुटपाथ का स्थान चुना. अपने मरीजों को वे वहीं बुलाने लगे.

प्रेगर अनुमति हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ज्योति बसु से भी मिले. उन्होंने उन्हें फटकार दिया, "यदि आप गरीबों की सेवा करना चाहते हैं तो इंग्लैंड वापस लौट जाइए." जब प्रेगर ने उनसे कहा कि कलकत्ता की सड़कों पर रहने वालों में बहुत लोग बीमार हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो प्रेगर के अनुसार, ज्योति बाबू ने नाराजगी से जवाब दिया, "इसके जिम्मेदार आप अंग्रेज लोग ही हैं." प्रेगर कहते हैं, "मार्क्सवादियों को यह विश्वास ही नहीं होता कि इंग्लैंड में इतना पैसा कमाने वाला डॉक्टर यहां मुफ्त में गरीबों की सेवा करना चाहता है. हम लोगों के विचारों में भारी मतभेद है. यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है." जाहिर है इस मतभेद का नुकसान अंततः शहर के गरीबों को ही उठाना पड़ेगा —कमलजीत रतन

गुजरात

सहानुभूति के सरोवर

सूखा राहत में स्वयंसेवी संस्थाओं का शानदार सहयोग

जब कभी कहीं सूखा पड़ता है, वायदों की बाढ़ आ जाती है. और इस बाढ़ का पानी जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है. लेकिन गुजरात कुछ मायने में अपवाद है. चार साल से चले आ रहे सूखे ने यहां खेतों और नदियों को भले ही सुखा दिया, सहानुभूति के सरोवरों को वह नहीं सुखा पाया है.

बंबई के करोड़पति हीरा व्यापारी 46 वर्षीय महेश भंसाली की ही मिसाल लीजिए. उन्होंने पिछड़े जिले बनासकांठा को पिछले छह महीने से अपना घर बनाया हुआ है. उनका मकसद: सूखापीड़ितों को कुछ राहत पहुंचाना. उनके परिवार का भंसाली ट्रस्ट राज्य की एक प्रमुख स्वयंसेवी राहत संस्था है.

या फिर दीपेंद्र पटेल का नाम लिया जा सकता है. तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारी पटेल पिछले चार महीने से बिना वेतन के छुट्टी पर हैं. दो बच्चों के पिता दीपेंद्र पूर्णकालिक राहत कार्यकर्ता हैं. वे सूखापीड़ित मवेशियों के लिए चारा जुटाने में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच आते-जाते रहते हैं.

अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई संकट आता है तो राज्य के लोग एक हो जाते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने सैकड़ों छोटी-बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं बना ली हैं. इनके जरिये वे सूखापीड़ित सौराष्ट्र और उत्तर व मध्य गुजरात में राहत कार्य कर रहे हैं. इन संस्थाओं के कामकाज में तालमेल बिठाने वाले सरकारी अधिकारी डी.जी. भट्ट कहते हैं, "अगर ये हाथ न बंटाते तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता."

ये राहत संस्थाएं 700 मवेशी शिविर चला रही हैं जिनमें 13 लाख मवेशियों की देखभाल की जाती है. माना जाता है कि सूखे से प्रभावित कुल मवेशियों की संख्या का यह लगभग चौथाई है. सरकार और ये संस्थाएं मवेशियों पर रोजाना 62 लाख रुपए खर्च करती हैं. इसमें से 22 लाख रुपए तो अकेले ये संस्थाएं जुटाती हैं.

और मवेशियों के मालिक ही नहीं, बल्कि

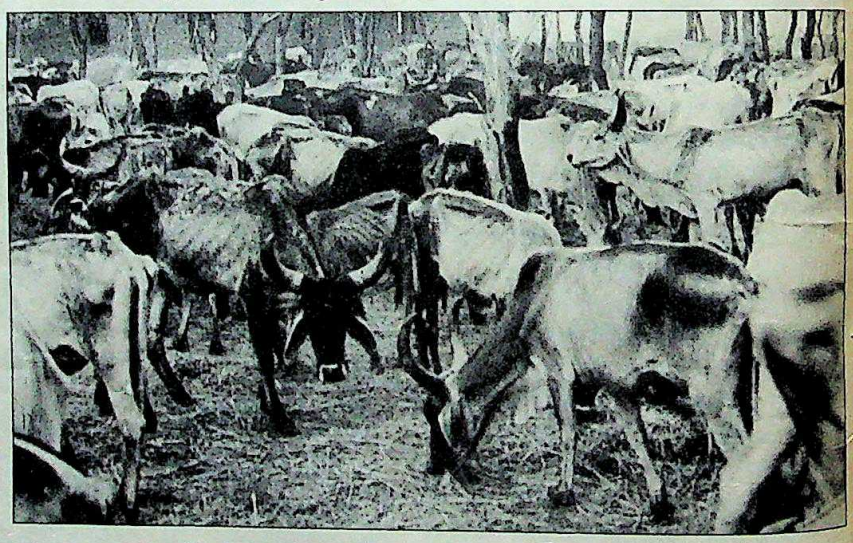

राधनपुर में मवेशी राहत शिविर

सरकार भी इन संस्थाओं का आभार मानती है. राहत कार्यों के लिए अधिकारियों को अपने कर्मचारियों से कहीं बहुत ज्यादा इन स्वयंसेवी संस्थाओं पर भरोसा है.

इन्हीं में से एक है भंसाली ट्रस्ट. उसने अपने कंधों पर बनासकांठा और सात दूसरे जिलों का जिम्मा लिया हुआ है. ऐसी ही एक और संस्था है 'सद्विचार परिवार' जो उत्तर और मध्य गुजरात में काम कर रही है. 'सर्व सेवा संघ' कच्छ के मवेशियों को आश्रय देता है. गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री से जुड़े कुछ व्यवसायियों द्वारा शुरू की गई संकट निवारण सोसाइटी ने भी मवेशियों के बचाव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए एक बड़ा काम शुरू किया है.

लेकिन सबसे सराहनीय काम भंसाली ट्रस्ट का है. इसे बंबई के हीरा व्यवसायी संघ से भारी धनराशि मिलती है. संघ के अध्यक्ष महेश भंसाली के भाई हैं. भंसाली ट्रस्ट बनासकांठा के राधनपुर तालुका स्थित अपने मुख्यालय से लगभग एक समानांतर प्रशासन ही चलाता है. यह 165 मवेशी शिविरों के लगभग डेढ़ लाख पशुओं पर रोजाना नौ लाख रु. खर्च करता है. इसमें से सात लाख रुपए चारे पर सब्सिडी के रूप में सरकार देती है. इसके अलावा यह ट्रस्ट रोजाना लगभग 20,000 लोगों को मुफ्त अनाज भी देता है. ट्रस्ट चार जिलों में 350 दुग्ध केंद्र भी चलाता है जहां से लगभग दो लाख लोग दूध लेते हैं. इस बीच सरकार ने ट्रस्ट को 20,000 किग्रा. सुखड़ी (गुड़, तेल और गेहूं से बनने वाला विटामिनयुक्त खाद्य) बनाने का काम सौंपा है. ट्रस्ट सरकार से मिलने वाले गेहूं, गुड़ और तेल से अपने तीन केंद्रों में सुखड़ी बनाता है और रोजाना लगभग ढाई लाख लोगों में बांटता है. पहले जरूरतमंद लोगों की शिनाख्त करता है और फिर उन्हें राशन के लिए परिचय-पत्र देता है. मवेशियों के खाने की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट ने एक छोटी फैक्टरी भी लगाई है. ट्रस्ट के अध्यक्ष भंसाली कहते हैं, "हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस मकसद के लिए पैसा दान किया गया है वह उसी में खर्च हो."

भंसाली अविवाहित हैं. बंबई का अपना आलीशान दफ्तर छोड़कर वे राधनपुर की चिलचिलाती धूप में रोजाना 16 घंटे राहत कार्यों की निगरानी में लगे रहते हैं. पिछले साल उन्होंने साढ़े चार करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे. इस साल लक्ष्य छह करोड़ रुपए इकट्ठा करने का है. उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से मदद मिली. दूरदराज के एक गांव में ट्रांसपोर्ट का छोटा-मोटा कारोबार करने वाले हसमुख दोषी ने अपना कारोबार अपने भाई को सौंप दिया और बनासकांठा में धन संग्रह अभियान में जुट गए. उन्होंने चार महीने में गांववालों से 35 लाख रुपए चंदा उगाहा.

उधर कच्छ में सर्व सेवा संघ के कारण 67,000 मवेशियों की जान बचाई जा चुकी है. हालांकि इस पर भाजपा और हिंदू समर्थक नेताओं का नियंत्रण है लेकिन इसने मुस्लिमबहुल इलाकों में भी अपने मवेशी शिविर खोले हैं. मिसाल के तौर पर संघ के भीरनदियारा शिविर के लगभग सभी 1,000 मवेशी मुसलमानों के हैं. 52 वर्षीय मोहम्मद वेलजी कहते हैं, "संघ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फर्क नहीं करता है." हाल ही में संघ ने जिले में एक सर्वे कर रतौंधी के 80,000 मामलों का पता लगाया. अब यह रतौंधी के शिकार लोगों को विटामिन 'ए' की गोलियां बांट रहा है कच्छ के जिलाधीश माहेश्वर साहू कहते हैं, "स्वयंसेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन के बीच अच्छा तालमेल होने के कारण सूखे से लड़ना आसान हो गया है." दुष्काल पीड़ित सहायता समिति भी रतौंधी को खत्म करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है.

लेकिन सद्विचार परिवार की प्राथमिकताएं अलग हैं. राहत कार्यों के बजाय सूखा नियंत्रण उपायों को ज्यादा महत्व देते हुए इसने बनासकांठा जिले में एक बांध और एक रिसन जलाशय बनाया है. इसके अलावा इसने 23 गांवों में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं भी शुरू की हैं. इसने सूखापीड़ित इलाकों में ढाई लाख पौधे लगाए हैं. दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर यह परती जमीन के विकास के लिए भी काम कर रहा है.

संकट निवारण में जो चाहे अपनी भूमिका निभा सकता है. यह राजकोट के सरगम स्पोर्ट्स क्लब ने साबित कर दिया है. इसने शहर में एक रसोईघर चलाकर 50 पैसे में भरपेट खाना देना शुरू कर दिया है. आज हालत यह है कि खाने के लिए यहां रोजाना 1,000 लोगों की लंबी लाइन लग जाती है. क्लब इस रसोईघर पर हर महीने एक लाख रुपए खर्च करता है.

गुजरात सरकार अपनी तरफ से इन स्वयंसेवी संस्थाओं को पूरा प्रोत्साहन दे रही है. इन्हें 300 करोड़ रु. का ब्याज-मुक्त कर्ज दिया गया है और दो उपयुक्त अधिकारियों को राहत कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है. राज्य के राहत आयुक्त वाई. दीक्षित और स्वयंसेवी संस्थाओं की समन्वय समिति के निदेशक डी.जी. भट्ट अपने कामों में बहुत रुचि लेते हैं. भट्ट कहते हैं, "निःस्वार्थ लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने से जीवन के प्रति मेरा रवैया ही बदल गया है अब मुझे अपने काम से बेहद संतोष मिलता है."

आखिर क्या कारण है कि गुजरातियों में परमार्थ कार्यों के प्रति इतना रुझान है. कई सामाजिक कार्यकताओं का मानना है कि यह जैन धर्म के प्रभाव के कारण है. लेकिन सद्विचार परिवार के 61 वर्षीय हरिभाई पंचाल दूसरा ही कारण बताते हैं. "सामाजिक कार्य तो गुजरातियों के खून में है." इसलिए ताज्जुब नहीं कि सूखे की मार के बावजूद उनका राज्य उम्मीद की लौ की तरह दिपदिपाता है.

—**उदय माहुरकर**, बनासकांठा, कच्छ और राजकोट से

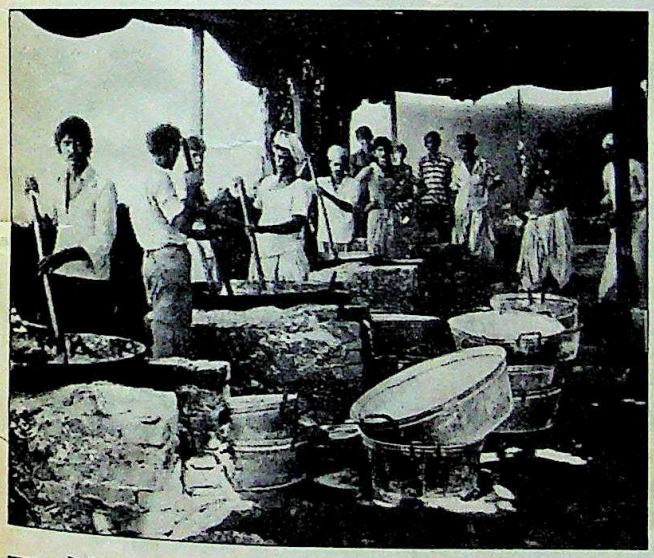

अरविंद मेहता

भंसाली ट्रस्ट का 'सुखड़ी' वितरण केंद्र (बाएं), और राजकोट का राहत केंद्रः सराहनीय प्रयास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मलेरकोटला

जिसे रोशन खुदा करे

सांप्रदायिकता के बवंडरों के बीच अमन व भाईचारे का द्वीप

लुधियाना और पटियाला को जोड़ने वाले राजमार्ग के दोनों ओर का दृश्य कुल मिलाकर पंजाब की अपनी खासियत ही उजागर करता है. दूर-दूर तक फैले गेहूं के खेत और बीच-बीच में कहीं-कहीं हरी सब्जियों के खेतों की हरियाली. लेकिन संगरूर जिले के मलेरकोटला कस्बे से करीब 50 किमी पहले से ही लोगों में फर्क दिखने लगता है. लगता है जैसे अतीत जीवंत होने लगा हो, वह अतीत, जब अविभाजित पंजाब के ज्यादातर शहर मुस्लिमबहुल थे. लेकिन विभाजन और उसके साथ घटी बर्बरता ने इस इलाके की आबादी का स्वरूप बदल दिया. और आज भी जब पंजाब एक दूसरी सांप्रदायिक त्रासदी की ओर बढ़ता दिख रहा है, मलेरकोटला में दूसरे संप्रदायों की तुलना में मुसलमानों की आबादी ही सबसे ज्यादा है.

विभाजन के बाद की बर्बरता अगर राजनीति और धार्मिक भेदभाव से उपजी असहिष्णुता का सबूत थी तो आज मलेरकोटला में मुसलमानों का बने रहना धर्म के मानवीय पहलू का जीता-जागता प्रमाण है. 1947 में जब पंजाब पर खूनी सांप्रदायिकता का पागलपन तारी था उस समय मलेरकोटला मानो शांति का एक द्वीप बना रहा. आज भी जब पंजाब के ज्यादातर हिस्से आतंकवाद की आंच में झुलस रहे हैं, इस कस्बे और इसके आसपास के गांव बहुत हद तक तनाव और हिंसा से मुक्त हैं.

इस कस्बे को एक विभूति का आशीर्वाद प्राप्त है और वह भी सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह का. अपने अनूठे भाग्य के लिए मलेरकोटला के निवासी 280 साल पहले घटी एक घटना की दुहाई देते हैं. 18वीं सदी के प्रारंभ में जब गुरु गोविंद सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब की सेनाओं के कारण भाग रहे थे तब उनका परिवार बिखर गया था. उनके बेटे—नौ वर्षीय जोरावर सिंह और सात वर्षीय फतेह सिंह—दुश्मन के हाथ लग गए. सरहिंद के मुगल सूबेदार की अगुआई में स्थानीय मुसलमान सिपहसालारों की एक सभा में दोनों लड़कों को दीवार के साथ चुनवा देने का फैसला किया. मलेरकोटला के नवाब शेर सिंह को छोड़कर बाकी सभी नवाबों ने इस पर रजामंदी जाहिर की थी.

श्याम टेकवानी

"मलेरकोटला ऐसा सुरक्षित स्थान बन गया था कि कई रातों से जगे शरणार्थी इसकी सीमा में पैर रखते ही जहां-तहां सो जाते थे"

मुहम्मद किफायतुल्ला, स्थानीय नेता

बाद में जब गुरु गोविंद सिंह को उनके बेटों के बारे में बताया गया तो उन्होंने पूछा कि क्या किसी मुसलमान सरदार ने मासूम बच्चों के साथ हुए इस जघन्य अत्याचार का विरोध किया. उन्हें सभा के फैसले के साथ शेर सिंह की असहमति की बात बताई गई. एक दंतकथा के अनुसार गुरु जी ने यह सुनकर एक बाण से घास का एक गुच्छा उखाड़ा और घोषणा की, "जालिमों की जड़ें उखड़ जाएंगी, लेकिन मलेरकोटला वालों की बेलें सदा हरी रहेंगी."

गुरु की भविष्यवाणी जल्दी ही सही साबित हुई. 1708 में दक्षिण में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य बंदा सिंह बैरागी पंजाब लौटे और उन्होंने सरहिंद तथा दूसरे मुगल सूबों पर हमला बोल दिया. लेकिन बदले की आग में जल रहे सिखों ने अपना कहर मलेरकोटला पर बरपा नहीं किया.

इसी तरह 1947 में भी जब दंगाई पूर्वी पंजाब में मुसलमानों को चुन-चुनकर मार रहे थे, यह कस्बा उनके पागलपन की गिरफ्त में आने से बचा रह गया था. आतंकित मुसलमानों को खदेड़ती हथियारबंद, खून की प्यासी भीड़ इस कस्बे की 162 वर्गमील की सीमा के बाहर ही रुक जाया करती थी. पटियाला से एकीकृत अकाली दल के सांसद चरणजीत सिंह वालिया याद करते हैं, "आसपास के इलाकों के कई मुसलमानों ने तब मलेरकोटला में आकर अपनी जान बचाई थी. ऐसी एक घटना मुझे याद है. पुराने 'पेप्सू' राज्य के हमीदी गांव के 500 मुसलमानों को 2,000 की भीड़ खदेड़ रही थी. लेकिन ये मुसलमान जैसे ही मलेरकोटला की सीमा में प्रवेश कर गए, भीड़ रुक गई और वहीं से लौट गई."

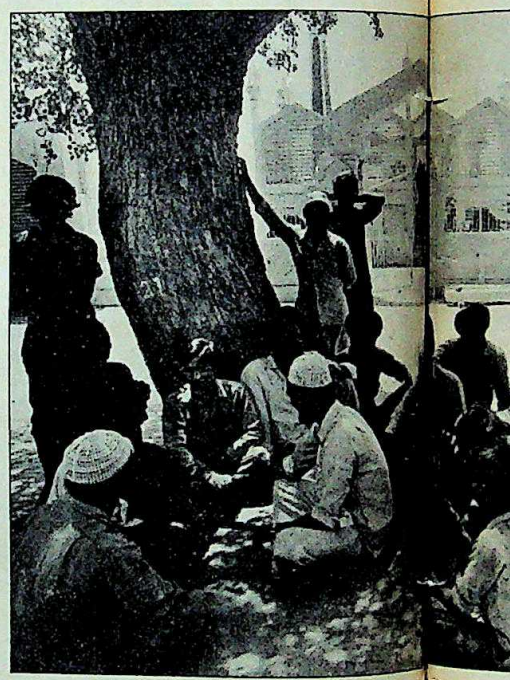

विभाजन के दौरान पूर्वी पंजाब में हुए दंगों में मुख्य हिस्सेदारी सिखों की ही रही थी लेकिन वे गुरु गोविंद सिंह के फरमान की कद्र करते थे. इसीलिए हजारों मुसलमान शरणार्थियों ने मलेरकोटला में शरण लेकर अपने को लगभग मौत के मुंह से बचा लिया था. 1948 में पाकिस्तान जाते हुए करीब दो लाख मुसलमान यहां रुके थे. पंजाब में अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू के सचिव मुहम्मद किफायतुल्ला याद करते हैं कि कैसे पूरा शहर शरणार्थियों की सहायता में जुट गया था जिनकी संख्या पूरे कस्बे की आबादी से भी अधिक हो गई थी. वे बताते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"मलेरकोटला ऐसा सुरक्षित स्थान बन गया था कि कई रातों से जगे शरणार्थी मलेरकोटला की सीमा में पैर रखते ही गेहूं के खेतों में जहां-तहां सो जाते थे."

विभाजन के पहले पंजाब की कुल 2 करोड़ की आबादी में 51 फीसदी मुसलमान, 33 फीसदी हिंदू, 14 फीसदी सिख और 2 फीसदी ईसाई तथा दूसरे संप्रदाय के लोग थे. आजकल भारत के इस उत्तर-पश्चिमी राज्य की आबादी 1.75 करोड़ है जिसमें 60.4 फीसदी सिख, 38.6 फीसदी हिंदू और 1 फीसदी मुसलमान और ईसाई हैं. मुसलमानों की कुल 1.3 लाख आबादी में से बहुसंख्य

प्रमोद पुष्करणा

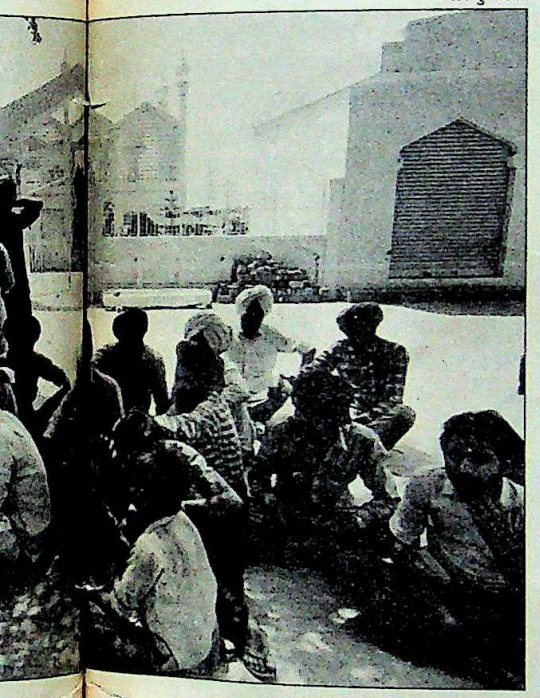

मलेरकोटला में सिख और मुसलमान

मलेरकोटला सबडिवीजन में रहती है. इस कस्बे को पंजाब का एकमात्र मुस्लिमबहुल कस्बा होने का अनोखा दर्जा मिला हुआ है. इसके 90,000 निवासियों में 26,000 मुसलमान, 25,000 हिंदू और 3,000 सिख हैं.

मलेरकोटला ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 1952 से अब तक पंजाब विधानसभा में मुसलमान सदस्य भेजता रहा है. वह कांग्रेसी रहा हो या किसी अकाली दल का, लेकिन वह नवाब परिवार का ही रहा. किफायतुल्ला बताते हैं, "यहां के मुसलमानों में राजनैतिक जागरूकता ज्यादा नहीं है. विभाजन के बाद से उन्होंने नवाब परिवार से ही उम्मीदें लगाए रखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नवाब ने ही उन्हें बचाया था."

विभाजन के तुरंत बाद ही नवाब अहमद अली खां की मृत्यु हो गई और उनके बेटे इफ्तिखार अली खां उनके उत्तराधिकारी बने. वे ही मलेरकोटला के पहले विधायक बने. इफ्तिखार अली के बाद उनकी तीन बेगमों में से दो—यूसुफ जमां और साजिदा बेगम—विधायक बनीं. हाल में भंग हुई विधानसभा में मलेरकोटला से नुसरत अली खां विधायक थे. उन्हें सुरजीत सिंह बरनाला ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था. वे 117 सदस्यों की विधानसभा में अकेले मुसलमान सदस्य थे. नुसरत अली कहते हैं, "आज पंजाब में मुसलमानों की हालत 20 साल पहले की तुलना में बेहतर है. 1965 के

प्रमोद पुष्करणा

"अब तीनों संप्रदायों—हिंदू, मुसलमान और सिख—के लोग यहां शांतिपूर्वक रहते हैं. यह यहां की परंपरा की ही देन है"

परमेश्वर दास, पेट्रोल पंप मालिक

भारत-पाक युद्ध के पहले तक सरकार की नजर में हर मुसलमान जासूस था. मुझे दो बार जेल भेजा गया और अमृतसर में बड़ी बेरुखी से मुझसे पूछताछ भी की गई. पर उस युद्ध में जब मुसलमान सैनिक भी बहादुरी से लड़े तब रवैया बदल गया."

पंजाब में सिख आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही राज्य का यह मुस्लिमबहुल क्षेत्र अपनी राजनैतिक हैसियत के प्रति और अधिक आश्वस्त महसूस करने लगा है. इसका कारण यह है कि उन्हें लगता है कि हिंदू और सिख दोनों ही उन्हें खुशहाल देखना चाहते हैं. राज्य के सिख हिंदुओं की तरह मुसलमानों के साथ भी बराबरी का रिश्ता महसूस करते हैं. मलेरकोटला में हिंदू भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. पंजाब में जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मुहम्मद अब्दुल रऊफ कहते हैं, "हिंदू कहते हैं कि वे मुसलमानों की वजह से ही सुरक्षित हैं. पंजाब में मुसलमान महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गए हैं. इसी कारण वे यहां बेहतर स्थिति में हैं."

निश्चित तौर पर मलेरकोटला ही एकमात्र ऐसा कस्बा रह गया है जहां विभाजन के पहले वाली पंजाबी संस्कृति अभी भी फल-फूल रही है. यह कस्बा सिर्फ हिंदी फिल्मों के स्टार धर्मेंद्र के लिए ही मशहूर नहीं है बल्कि यह अपने कवियों, लेखकों और कव्वालों के लिए भी मशहूर है. पंजाब के साहित्य में इस कस्बे ने उर्दू शायरी और उर्दू कहानी का योगदान तो किया ही है, मुश्ताक वारसी जैसे लेखकों के माध्यम से इसने पंजाबी भाषा को भी जीवित रखा है. शायर खालिद किफायत कहते हैं, "हम जिस पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह वही है जो 'हीर' जैसे महाकाव्य की है. पंजाबी और उर्दू की बनावट एक जैसी है और इन दोनों भाषाओं के बीच रफ्त-जफ्त फायदेमंद साबित हुआ है." मुसलमानी सामंती संस्कृति की कुछ रंगारंग प्रथाएं भी आज यहां जीवित हैं.

मलेरकोटला में औद्योगिक विकास का दौर कुछ देर से शुरू हुआ. 1978 में जब सरकार ने इस इलाके को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया था तभी कुछ कारखाने यहां लगे. उसके बाद ही इस सबडिवीजन में करघे, इंजीनियरिंग, खेलकूद के सामान और कृषि यंत्रों के कारखाने लगे. बैडमिंटन रैकेट बनाने वाले रशीद ब्रदर्स के मालिक अब्दुल रशीद कहते हैं, "भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी भी है. लेकिन मलेरकोटला के मुसलमानों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि वे आलसी हैं."

जट्टीवाल इस सबडिवीजन के मुसलमान-बहुल गांवों में से एक है. आजादी के बाद यहां से सिर्फ तीन परिवार ही पाकिस्तान गए. शफी मुहम्मद कहते हैं, "भारत में हर कोई बराबर है. यहां से जाने का ख्याल हमारे मन में कभी नहीं आया. आज भी जट्टीवाल में रहकर हमें नहीं लगता है कि पंजाब में कोई गडबड़ी फैली हुई है."

मलेरकोटला के शासक वर्ग के लोगों के सभी संप्रदायों से विशेष रिश्ते हमेशा बने रहे. तभी तो नवाब इफ्तिखार अली के ढहते महल की दीवारों पर गुरु गोविंद सिंह और स्वर्णमंदिर के चित्र देखे जा सकते हैं. इफ्ति-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्याम टेकवानी

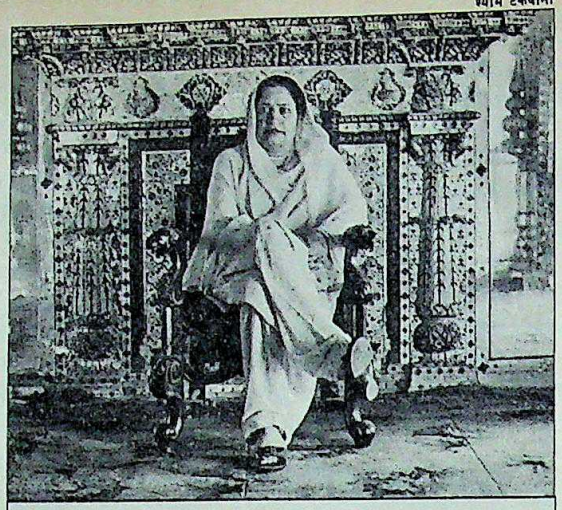

"यहां एक दूसरे के त्यौहारों में भाग लेने की परंपरा आज भी जारी है. ऐसा शायद ही कहीं होता हो"

साजिदा बेगम, राजनीतिक

खार अली की एक विधवा मुनव्वरुन्निशा बेगम का दावा है कि उनके पास सिख गुरु की एक चिट्ठी और एक तलवार है. शहर के संस्थापक फकीर शेख सदरुद्दीन की दरगाह पर मुसलमानों के बजाय सिख ही ज्यादा जाया करते हैं. और इस शहर में न तो गाय का और न सुअर का मांस मिलता है.

विभाजन के समय भड़की हिंसा के दौरान मलेरकोटला के प्रायः सभी हिंदू इस कस्बे से चले गए थे. तब यहां रुके रहे चार हिंदुओं में से एक, 91 वर्षीय परमेश्वर दास, जो अब एक पेट्रोल पंप के मालिक हैं, कहते हैं, "तीनों संप्रदायों के लोग यहां शांति से रहते हैं. यह यहां की परंपरा की ही देन है." राजनीति में आने के बाद नवाब से तलाक लेने वाली साजिदा बेगम कहती हैं, "ऐसा भाईचारा बमुश्किल दिख पड़ता है. यहां एक-दूसरे के त्यौहारों, उत्सवों में साझेदारी की परंपरा है. ऐसा तो हिंदुस्तान में आप शायद ही कहीं देख पाएं."

दुर्भाग्यवश करीब साल भर से मलेरकोटला के इस रंग में भंग डालने के खतरे दिखने लगे हैं. यहां कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ. 1983 में एक मामूली घटना घटी थी लेकिन स्थानीय प्रशासन ने तुरंत उस पर काबू पा लिया था. लेकिन अब कुछ हिंदुओं और मुसलमानों के अलग-अलग खेमे बनने लगे हैं. मसलन, मुसलमान नेताओं के विरोध के बावजूद एक पूर्व विधायक अनवर अहमद खां ने, जो अब एकीकृत अकाली दल में हैं, शहर में कट्टरपंथी 'आदम सेना' की शाखा पिछली मई में स्थापित कर दी. जवाब में हिंदू सुरक्षा समिति के पवन कुमार शर्मा और शिवसेना के जगदीश टांगड़ी रामनवमी के जुलूस का नेतृत्व करने मलेरकोटला पहुंचे. सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट एस.एस. ग्रेवाल कहते हैं, "दोनों में से कोई पक्ष जनसमर्थन जुटाने में कामयाब नहीं रहा. लेकिन मलेरकोटला में ऐसी गतिविधियां असामान्य ही हैं."

पिछले अक्तूबर में एक पुलिस अफसर के द्वारा एक मुसलमान फल बेचने वाले की निर्मम हत्या से माहौल तनावग्रस्त हो गया था. फल बेचने वाले ने जब एक सिख पुलिस अफसर से फल की कीमत मांगी तब पुलिस अफसर ने उस पर एकदम नजदीक से गोली दाग दी थी. हत्या की खबर फैलते ही हजारों क्रुद्ध मुसलमानों की भीड़ अस्पताल में जुट गई जहां शव रखा था. लेकिन पुलिस और अल्पसंख्यकों की सीधी भिड़ंत सीआरपी की तुरत-फुरत कार्रवाई और मुसलमान नेताओं के शांति प्रयासों के कारण होते-होते टल गई.

उत्तेजना का दूसरा कारण सिखों द्वारा शहर से दस किमी दूर रोहिडा गांव के पास जमीन के एक प्लॉट की मांग को लेकर है. ये सिख मध्ययुग में अफगान खानाबदोशों द्वारा की गई सामूहिक हत्या में मारे गए सिखों का स्मारक बनाने के लिए जमीन की मांग अरसे से कर रहे हैं. समस्या यह है कि इस मुसलमानबहुल गांव में उस जमीन के मालिक भी मुसलमान ही हैं. मुसलमानों और सिखों के रिश्ते में तनाव तब और भी उभरने लगता है जब मुसलमान नेता विभाजन के दौरान मस्जिदों पर सिखों के कब्जे और मुसलमानों के जबरन धर्म-परिवर्तन की बातें उठाते हैं.

इतना साफ दिखता है कि पंजाब में मुसलमान ज्यों ही अपनी राजनैतिक अहमियत पर जोर देने लगेंगे, वहां हो रही उथल-पुथल से वे शायद बचे नहीं रह पाएंगे. चंडीगढ़ में अब मुसलमानों की आबादी करीब 10,000 है. इनमें से ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए हैं. लेकिन पिछले महीने राज्य के आतंकग्रस्त जिलों में मुसलमान परिवारों पर सिख आतंकवादियों के हमले की खबरें भी मिली हैं. व्यास के शरणार्थी शिविर में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और कपूरथला जिलों के 57 गांवों से आए 135 परिवारों में से 50 परिवार मुसलमानों के हैं. इन सभी परिवारों का कोई न कोई सदस्य आतंकवादी हिंसा में मारा गया है.

पंजाब जबकि भविष्य की तरफ आशंका भरी नजरों से देख रहा है, ये विभाजन की विपदा झेल चुके लोग ही हैं जो प्रार्थना करते रहते हैं कि इतिहास दुहराया न जाए. मलेरकोटला में कम-से-कम 10 फीसदी ऐसे मुसलमान हैं जो पंजाब के दूसरे इलाकों में सब कुछ गंवाने के बाद यहां आकर बस गए थे. ऐसी ही एक शरणार्थी हैं 70 वर्षीया जन्नी जिनका धुरी के नजदीक एक गांव में उनके छह साल के बेटे के साथ अपहरण कर लिया गया था. उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी. उन्होंने कई सालों के बंदी जीवन के बाद छुटकारा पाया और मलेरकोटला में आकर शरण ली.

यहां उनके बेटे मुहम्मद लतीफ अब खेत जोतकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. अपने आंसुओं को रोकते हुए जन्नी बताती हैं, "या खुदा सब कुछ बरबाद हो जाए तो हो जाए पर वह वक्त दुबारा लौटकर न आए."

—एम. रहमान

नई निर्माणाधीन मस्जिद

प्रमोद पुष्करणा

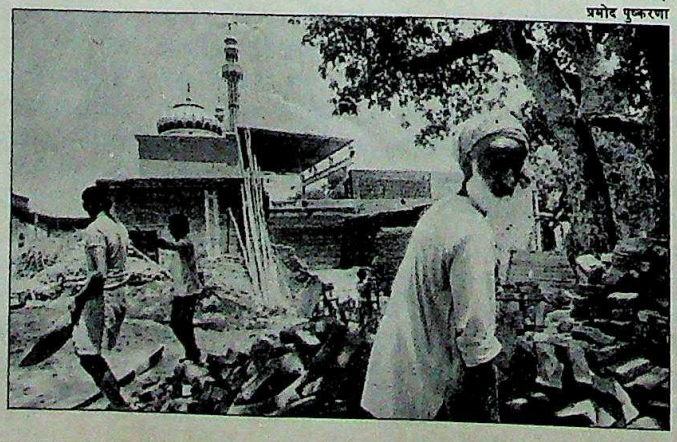

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ट्रेन्डी इरा

ग्रेविरा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ग्रेविरा सूटिंग्स

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रामायण

राम नाम की लूट है

धारावाहिक की रिकार्ड तोड़ लोकप्रियता से व्यापारियों की चांदी

सीताराम चरित अति पावन...प्रत्येक रविवार की सुबह लगभग पौने दस बजे टीवी सेटों पर ज्यों ही यह भजन गूंजता है, पूरा हिंदुस्तान मानो कुछ मिनटों के लिए एकदम ठहर-सा जाता है. शहरों की सडकें तकरीबन सूनी हो जाती हैं और गांवों की गलियां लगभग वीरान. लोग अपने या पड़ोसी या सामुदायिक टीवी सेट के सामने आ जुटते हैं. रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक 'रामायण' का कुछ ऐसा ही मनमोहिनी जादू-सा छा गया है लोगों पर.

एक अनुमान के मुताबिक इस धारावाहिक के दर्शकों की संख्या करीब छह करोड़ है. इसके सम्मोहन से बिंधने वालों में हर तबके के लोग हैं— नेता भी और किरानी भी, मजदूर भी और व्यापारी भी. 35 मिनटों की इस 'पवित्र अवधि' में कई 'छोटे-मोटे' काम टाल देने के उदाहरण सामने आए हैं, मसलन मंत्रियों ने शपथ लेना टाल दिया, तो एक राष्ट्रपति ने एक संपादक को समय देकर मिलना टाल दिया, रेलगाड़ियों ने उन स्टेशनों से आगे बढ़ना टाल दिया जिनके प्लेटफार्मों पर टीवी सेट लगे थे भले ही वहां उनका ठहराव तय नहीं था, विमानों ने उड़ना मुल्तवी कर दिया. मगर चतुर चोरों ने चोरी करना नहीं टाला क्योंकि वे जानते थे कि घरवाले टीवी सेट से आंखें हटाना गवारा नहीं करेंगे और उनका काम बन जाएगा.

इस धारावाहिक की महिमा भी निराली है. भावुक दर्शक किसी की मौत देखकर दुखी हो जाते हैं तो कभी राम के मूर्च्छित हो जाने से दहल जाते हैं. और कभी इस दौरान बिजली गुल हो गई तो उनका कहर बिजली विभाग पर टूटता है. राम और भरत का प्रेम देखकर दो कलियुगी भाइयों ने अपनी दुश्मनी भुला कर मेल-मिलाप कर लिया. और तो और, टीवी के राम और हनुमान चुनाव प्रचार करने भी पहुंच गए. और सबसे तो बन आई आतंकवादियों की जिन्होंने बाजार में 'रामायण' देख रहे दर्शकों को निशाना बना लिया.

लेकिन चांदी काट रहे हैं व्यापारी. 'रामायण' के प्रति दर्शकों का यह मोह उनके लिए सोना बरसाने वाला साबित हुआ है. इस धारावाहिक के वीडियो कैसेट धड़ाधड़ बिक रहे हैं. और इस महाकाव्य के कथानक पर लिखी किताबों की बिक्री कई गुना बढ़ गई है. स्टालों पर रामायण से संबंधित कथाओं के कॉमिक्स की ढेर लग गई है. बच्चों के लिए खिलौनों के रूप में गदाओं और तीर-कमानों की भरमार दुकानों में लग गई है. और अपनी छवि के प्रति सचेत कंपनियां रामायण से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाने लगी हैं. यानी राम नाम की लूट है!

रामायण के इस व्यापारिक इस्तेमाल से जितने दुखी शायद बाल्मीकि होते, उतने ही दुखी आज सागर वीडियो के कर्ताधर्ता और रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर भी हैं. हालांकि उनके दुख की वजह और है. उनकी शिकायत है, "कॉपीराइट संबंधी हमारे कानून इतने दकियानूसी हैं कि आज कोई मेरी अनुमति के बिना रामायण के कलाकारों के चित्र इस्तेमाल करता है तो हम उस पर मुकदमा भी नहीं चला सकते."

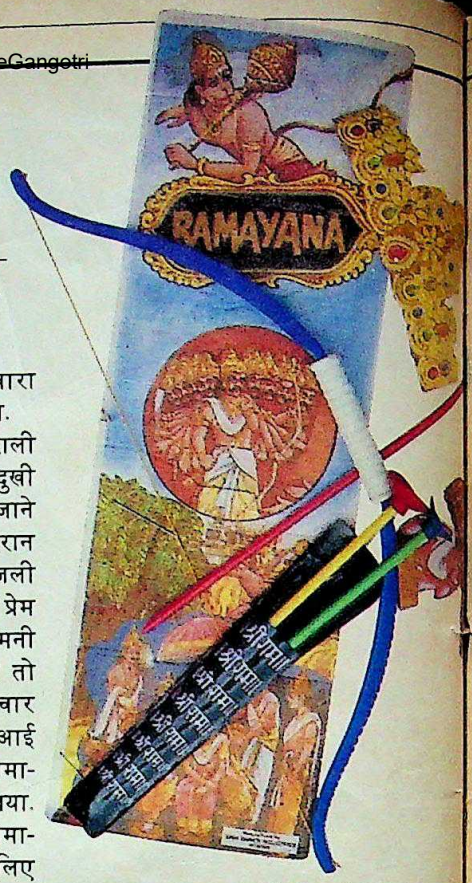

रामायण खिलौने: नई पौध

चित्रकथाओं और पुस्तकों की मारी बिक्री

बहरहाल, सागर वीडियो की कामयाबी चौंकाने वाली है. पश्चिमी क्षेत्र में इन कैसेटों की बिक्री करने वाले एमरेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य अधिकारी अरुण टपलू का अनुमान है कि तीन प्रकरणों वाले एक वीडियो टेप के 18,000 कैसेट बेचे जा चुके हैं. एक वीडियो टेप की कीमत लगभग 325 रु. है. अब तक 12 वीडियो टेप बाजार में पहुंचे हैं. उम्मीद है कि 14 और वीडियो टेप बाजार में आने वाले हैं. कारोबार लगभग 15.06 करोड़ रु. के आसपास होना चाहिए.

जनता के इस भक्ति उन्माद को भुनाने की और भी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं. टपलू बताते हैं कि अब तो बाजार में सीता और राम की गुडिया-गुड्डे भी आने लगे हैं. रामायण के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है. प्रेम सागर बताते हैं कि इस धारावाहिक के खत्म होने के बाद 'रामायण' के केवल संवादों और संगीत का टेप एचएमवी की ओर से जारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया जाएगा. इस धारावाहिक के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के अधिकार लंदन के एक वितरक को बेचे जा चुके हैं.

इधर बंबई की एक चाय कंपनी हसमुख-राय ऐंड कंपनी ने अखबारों के जरिये 'रामायण ज्ञान प्रतियोगिता' आयोजित की, जिसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया. एक्सप्रेस समूह के फिल्म साप्ताहिक 'स्क्रीन' ने सागर वीडियो के सहयोग से रामायण पर आधारित फिल्मों के ऊपर एक प्रतियोगिता आयोजित की.

'रामायण' के कथानक पर छपी किताबों की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है. भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित सी. राजगोपालाचारी की पुस्तक 'रामायण' की छह लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं. विद्या भवन ने रामायण पर आधारित 12 और पुस्तकें प्रकाशित की हैं.

दूसरे प्रकाशक भी पीछे नहीं रहे हैं. वाइकिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित आर.के. नारायण के रामायण का संस्करण भी लोकप्रिय हो रहा है. आर.पी. गोल्डमैन ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद चार खंडों में किया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित इन खंडों (कीमत 350 रु.) की भी खासी मांग है. हरप्रसाद शास्त्री का ग्रंथ इनमें सबसे महंगा (750 रु.) है. ओरिएंट लांगमैन ने एक सचित्र रामायण प्रकाशित की है जिसकी कीमत 225 रु. है. इसमें आलेख लक्ष्मी लाल के और चित्र बद्री नारायण के हैं.

बच्चों के लिए तो विकल्प की कमी नहीं. चित्रकथाओं के सरताज— इंडिया बुक हाउस के अमर चित्रकथा की पुस्तकों की तुलना किसी भी अन्य सचित्र पुस्तकों से की जा सकती है. 16 चित्रकथा पुस्तकों की बिक्री में धारावाहिक शुरू होने के बाद 20 फीसदी वृद्धि हुई है. 'द स्टोरी ऑफ राम' नामक चित्रकथा की तो पांच लाख से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं. बिक्री बढ़ाने के लिए अमर चित्रकथा के संपादक अनंत पई ने एक नई श्रृंखला सीरीज— अमरकथा शुरू की है. किशोरवय बच्चों के लिए चार भागों में प्रकाशित (हर भाग की कीमत 20 रु.) इस चित्रकथा में चित्र कम, कथा अधिक है.

दिल्ली के ड्रीमलैंड पब्लिशर्स और आर्नोल्ड पब्लिशर्स भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं. ड्रीमलैंड ने 60 रुपए कीमत वाली रामायण चित्रकथा 12 खंडों में छापी है. प्रेम सागर ने आर्नोल्ड की मदद से 240 रुपए कीमत वाली चित्रकथा आठ खंडों में छापी है. ड्रीमलैंड इससे भी एक कदम आगे महाभारत चित्रकथा बाजार में लाने वाला है, जो ठीक उस वक्त जारी होगी जब बी.आर. चोपड़ा

इस धारावाहिक के सम्मोहन से बिंधने वालों में नेता भी हैं, किरानी भी और मजदूर भी, व्यापारी भी. व्यापारियों के लिए यह सोना बरसाने वाला साबित हुआ है

का धारावाहिक 'महाभारत' टीवी पर दिखाया जाएगा.

लेकिन इन सब में हैदराबाद के श्रीनिवास राव की योजना सबसे साहसपूर्ण है. उन्होंने राम लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई है और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को भारत की सीमा तक सीमित नहीं रखा है. बच्चों के लिए हनुमेट्स क्लब बनाने के अलावा टीवी की कार्टून फिल्में, चित्रकथा और कंप्यूटर ग्रॉफिक्स बनाने की भी उनकी योजना है. जुलाई में राम लि. की हनुमान चित्रकथाएं बाजार में आ जाएंगी. राव का पहले साल में 4 करोड़ रु. का कारोबार करने का लक्ष्य है.

अपने क्लब के बारे में राव बताते हैं कि क्लब की सदस्यता के लिए उनके पास 25,000 अर्जियां पहुंच चुकी हैं. क्लब के हर सदस्य को एक कार्ड दिया जाएगा जिस पर उसके बारे में निजी जानकारियां दर्ज होंगी. इस कार्ड से बच्चे चित्रकथाओं, पत्रिकाओं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, खेल के विशेष कपड़ों और दूसरे सामान पर छूट पा सकेंगे. राव कहते हैं, "बच्चों के लिए यह कार्ड हैसियत का प्रतीक होगा."

राव जहां बच्चों में हैसियत के प्रति आग्रह जगाना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनमें उत्तेजना और हिंसा की भावना जगाना चाह रहे हैं. बच्चों ने मुखौटे पहन कर तीर-कमान व गदे उठा लिए हैं. हनुमान का मुखौटा खूब बिक रहा है. और बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें देने के लिए धनुष-बाण का तोहफा सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा है.

लेकिन अब यह केवल मौज-मजे का खेल नहीं रह गया है. मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में 12 बच्चे और मंदसौर जिले में 9 बच्चे तीर-कमान के इस खेल में अंधे हो गए. पश्चिम बंगाल में पिछले पखवाड़े लंका जलाने की नकल करते हुए एक बच्चे ने पीठ जला ली. सौराष्ट्र में दो बच्चों की मौत भगवान हनुमान की तरह उड़ने की कोशिश में छत से छलांग लगाने से हुई.

बच्चों में इसकी वजह से फैल रही हिंसक प्रवृत्ति ने लोगों को चिंतित किया है. बंबई में बाल विकास और शिक्षा केंद्र चलाने वाले शिक्षाविद रोशन मंडकर कहते हैं, "बच्चे चाहे जिस किसी प्रकरण की नकल करें, अंत प्रायः लड़ाई से ही होता है." धारावाहिक में महिलाओं के चित्रण आदि को लेकर भी महिला संगठनों ने सवाल उठाए हैं.

लेकिन आलोचनाएं अक्सर प्रशंसा के शोरगुल में खो जाती हैं. चित्रकार बद्री नारायण इसकी लोकप्रियता की वजह बताते हैं, "आज आदमी अपने वक्त की मान्यताओं के प्रति बेहद शंकालु है. रामायण उसे बताती है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद वह जिंदगी कैसे जिए, कैसे ईमानदारी का आचरण करे." धारावाहिक की लोकप्रियता की वजह चाहे उसका दार्शनिक तेवर हो या भारतीयों को आकर्षित करने वाला फिल्मी कथानक, एक बात साफ है कि व्यापारी वर्ग अगर राम नाम की टेर लगा रहा है तो महज भक्ति भाव से नहीं.

—**सलिल त्रिपाठी** भोपाल में **नरेंद्र कुमार सिंह**, लखनऊ में **दिलीप अवस्थी** और दिल्ली में **नंदिता सरवाना** की रिपोर्टों के साथ

धारावाहिक के वीडियो कैसेट्स

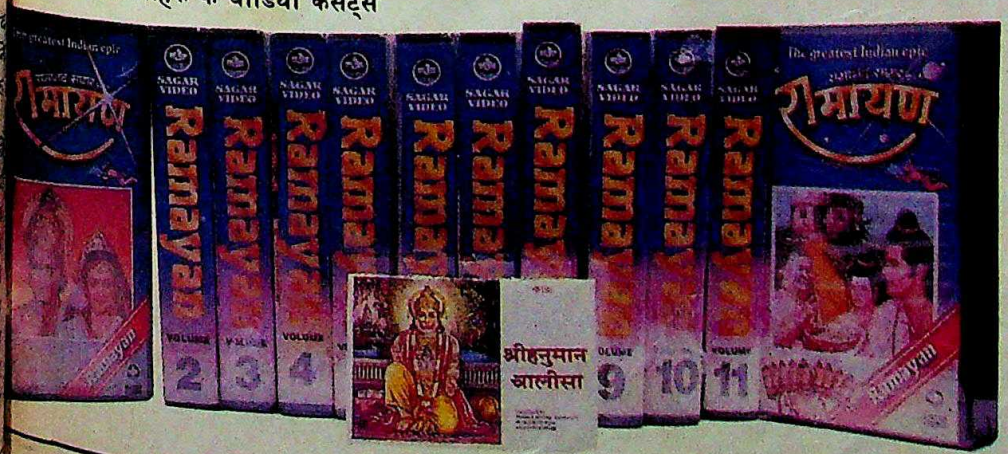

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• बंबई में इतालवी फैशन के एक अंधड़ जैसा था यह फैशन टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस फैशन शो में फिल्म नगरी की कई हसीनाओं ने भाग लिया और नामी इतालवी डिज़ाइनरों—फेरे, बिबलोस और बाजील के बनाए गर्मी के परिधानों का प्रदर्शन किया. इस मौके पर इटली के एक वस्त्र निर्यात विशेषज्ञ जियांफांको मेली की टिप्पणी थी, "फैशन के प्रति अधिक जागरूकता के लिए भारत को डिजाइनिंग की ओर अधिक ध्यान देना होगा." इस शो की एक मुख्य उपलब्धि थी 25 वर्षीया मॉडल **रेशमा वासा** जिसने दर्शकों का मन मोह लिया.

• फैशन है कि ज्यों ही सितारे गर्दिश में दिखाई दें, फिल्मी सितारों को अपने रथ की लगाम सौंप दो. इलाहाबाद में इंका ने यही कोशिश की. लेकिन बेचारे 'मर्यादा पुरुष' आर सी साहू

तीजन बाईः चुनावी जादू

अरुण गोविल के सभी तीर बेअसर रहे. मगर इस मामले में **तीजन बाई** अपना कमाल दिखाने में कामयाब रहीं जिन्होंने मध्य प्रदेश के खरसिया चुनाव क्षेत्र में अर्जुन के प्रचार रथ की कमान संभाली. 1985 में फ्रांस में हुए भारत महोत्सव में पंडवाणी शैली में महाभारत प्रस्तुत करके उन्होंने पेरिसवासियों का मन जीता था और पिछले पखवाड़े उन्होंने अर्जुन सिंह के मतदाताओं को भी अपने जादू से मोह लिया. तीजन बाई का दावा था कि अर्जुन 'इंदिरा माता के सपनों' को साकार कर देंगे. सपने जब साकार होंगे तब होंगे, अब कम वोटों की जीत ने खुद अर्जुन का मोहभंग कर दिया है.

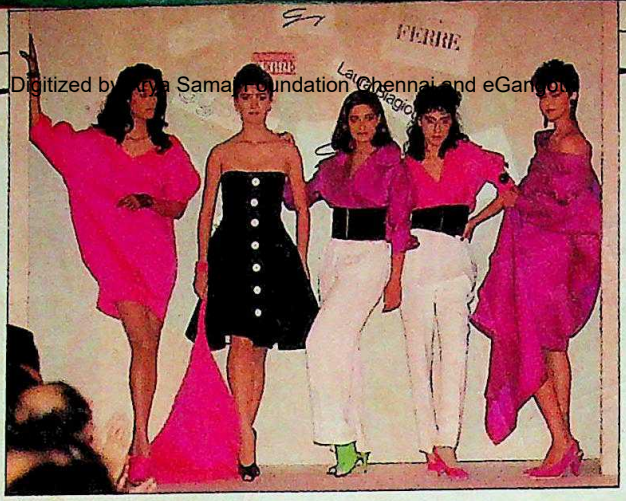

फैशन शो में मॉडलः इतालवी फैशन

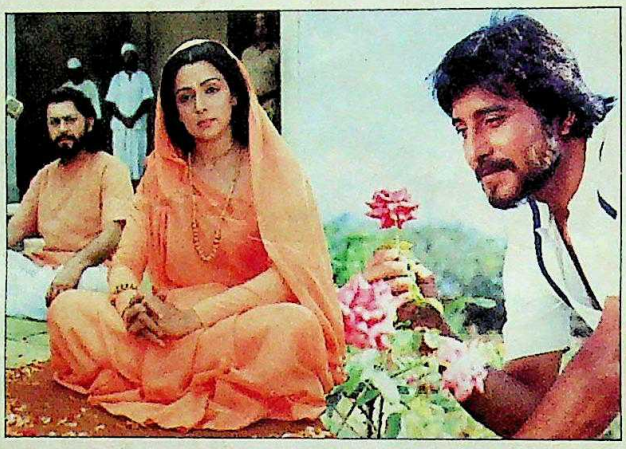

हेमा और विनोद खन्नाः आध्यात्मिक खोज

वैसे तो उन्हें तने चेहरे और कठोर हृदय वाली महिला के रूप में जाना जाता है लेकिन कभी-कभी उनमें वात्सल्य भी फूट पड़ता है. पिछले पखवाड़े संजय गांधी की आठवीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने आए राजीव और सोनिया को जब संजय के पुत्र वरुण ने देखा तो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया. मौके की गंभीरता को देखते हुए राजीव तो हाथ ही हिलाकर रह गए मगर सोनिया पल भर के लिए देवरानी मेनका की कड़वाहट भूलकर दौड़ी आईं और वरुण को गले लगा लिया. आसपास खड़े लोग भौंचक रह गए. शायद वे भी महसूस कर रहे थे कि पारिवारिक रिश्ते राजनैतिक संबंधों से ज्यादा गहरे होते हैं.

एस.के. चड्ढा/टाइम्स ऑफ इंडिया

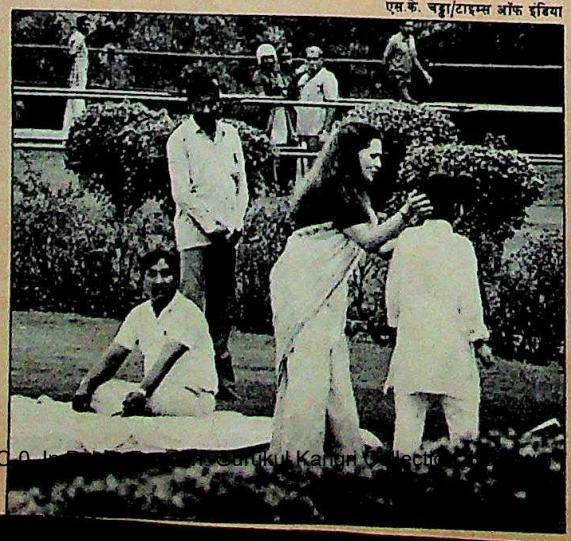

• और अब **हेमा मालिनी** का अगला निशाना धार्मिक संस्थानों में चलने वाली राजनीति है. अभिनेत्री से निर्माता बनी हेमा की नई फिल्म 'मार्ग' में एक आश्रम की अंदरूनी कहानी है. फिल्म में आचार्य रजनीश के आश्रम से जुड़े रहे तीन लोग भी हैं. हेमा ऐसे ही एक आश्रम की देवी माता है. वह एक अपराधी (जी हां, विनोद खन्ना) पर रीझ जाती है जो अब शांति की खोज में है. फिल्म के निर्देशक और आश्रम के मामले में अनुभवी **महेश भट्ट** कहते हैं, "अध्यात्म मुझे काफी देर से झकझोरता आ रहा था." शायद इसलिए आश्रम के एक पुराने भक्त और पटकथा लेखक सूरज सनीम के साथ वे इस सचाई को नंगा करने में जुटे हैं कि कैसे भक्ति एक व्यापार बन चुकी है. देखें उनके पूर्व गुरु की क्या राय बनती है इस फिल्म के बारे में.

• छह साल की यह लड़की 50 विज्ञापन फिल्मों और अखबारी विज्ञापनों में अपना चेहरा दिखा चुकी है. उसके पास फिल्मों में काम के दर्जनों प्रस्ताव हैं. 'आई लव यू रसना' की ख्याति वाली **अंकिता जावेरी** ने आठ महीने की उम्र से ही कैमरे से दो-चार होना शुरू किया था. जल्दी ही वह एक नए टीवी सीरियल 'शेष' में 'बुनियाद' के चर्चित कलाकारों आलोक नाथ और अनिता कंवर के साथ उनकी बेटी के रूप में आने वाली है. लेकिन बंबई के ग्रीन लांस स्कूल में पढ़ रही और एक नामी जौहरी परिवार में

अंकिताः बाल लोकप्रियता

जन्मी इस बच्ची के मां-बाप उसके फिल्मी कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं हैं. खुद अंकिता का भी कहना है, "बड़ी होने पर मैं एक चित्रकार बनना चाहूंगी."

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

EGISTRATION NO. R.N. 45823/88

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अल्फा की कीमत दूसरों के मुकाबले देखिये

एल एम एल वेस्पा

रु.11,000/-*

* लगभग

इंजन : अति आधुनिक 3- पोर्ट इंजन जो केवल 5500 आर पी एम पर 8 बी.एच.पी. शक्ति उत्पन्न करता है।

इलेक्ट्रॉनिक इग्नीशन : कांटेक्ट ब्रेकर प्वाइंट की जरूरत नहीं। रखरखाव की परेशानी से मुक्त, तत्काल स्टार्ट और बेहतर इंजन क्षमता।

हैन्डिलबार : बैठने के लिये ऐसी व्यवस्था जिससे सवारी में आसानी और थकान कम से कम।

बॉडी लाइन : खूबसूरत बॉडी लाइन जो एल एम एल वेस्पा को अन्य स्कूटरों से कहीं बेहतर बनाती है।

सस्पेन्शन : स्थिरता और संतुलन के लिये अनूठा एक्टिंग फ्रंट सस्पेन्शन।

ब्रेक : न जकड़ने वाली, कम घिसने वाली प्रणाली।

सुविधाजनक कार जैसी पुश टाईप सुरक्षित बेकिंग व्यवस्था।

कहिये ! यह सब देखने के बाद भी मुकाबला।

अल्फा की खूबियाँ देखिये और मुकाबला भूल जाइए

एल एम एल वेस्पा अल्फा

everest/d8b/KP178 hin

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मस्ती का आलम!

PARAG ZARDA

अपने हर पल को और मज़ेदार बनाइए, पराग ज़र्दे के संग।

इसका अनोखा स्वाद बेहतरीन तम्बाकू के लाजवाब मेल का नतीजा है — जो उसी सावधानी से बनाया जाता है जैसे आपका मनपसन्द पान पराग।

बस, अपनी पसन्द का ज़र्दा चुनिए, 110 या 50 न० – और पराग ज़र्दे की 'मस्ती' और ताज़गी का आनन्द लीजिए।

पराग®
ज़र्दा

वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Contract. JCT.20103/88-1 HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 2, अंक: 18, 16-31 जुलाई, 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद , हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली ; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास ; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर ; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

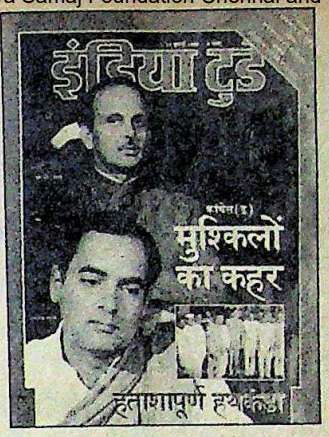

चेतने का संदेश

आवरण कथा (15 जुलाई) पढ़कर लगा कि इन उपचुनावों के जरिये देश का मतदाता एक बार फिर विपक्ष को आजमाना चाहता है. अब प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री बदलें या अपने मंत्रिमंडल की फौज बढ़ाएं, अगले आम चुनावों में मुकाबला निश्चय ही संघर्षपूर्ण होगा.

—चेतन चौहान, जोधपुर (राज.)

■ इन उपचुनावों से इंका को निश्चय ही धक्का लगा है. इलाहाबाद में तो जाति व धर्म के समीकरणों को ढहाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह जीते हैं. इससे पता चलता है कि उनके जो आरोप राजीव सरकार पर हैं वो कुछ हद तक सही हैं. इंका को लाल बहादुर शास्त्री का नाम भुनाते देख भी आश्चर्य हुआ कि हमेशा नेहरू खानदान का जाप करने वाली इंका को उनकी याद कैसे आई. इसकी वजह शायद यह थी कि वी.पी. सिंह की टक्कर का कोई और ईमानदार नेता उसके पास है ही नहीं.

—राजेश अरोड़ा, मसूरी (उ.प्र.)

उषा रोशनी फैलाए

ओलंपिक खेलों के लिए पी.टी. उषा की तैयारियों ('परों को तोलती उड़नपरी': 15 जुलाई) के बारे में पढ़ा. प्रशिक्षक सैनी का कथन ज्यादा उपयुक्त है कि "जहां कुछेक माइक्रो सेकेंड के अंतर से फैसला हो जाता हो, वहां भविष्यवाणी करना धोखेबाजी है." इसलिए पहले से ही उषा की सफलता पर संदेह करना और उसे मानसिक रूप से कमजोर बनाने वाले बयान देना ठीक नहीं. उषा देश की शान है. उसकी सफलता उसकी इच्छाशक्ति व दमखम पर ही निर्भर है. हम तो यही चाहेंगे कि वह और ऊंची उड़े और देश का नाम ऊंचा करे.

—राजेंद्र कुमार, भोपाल (म.प्र.)

दावों की धज्जियां

'धमाकों से थमीं धड़कनें' (15 जुलाई) पढ़ा. कुरुक्षेत्र में हुए बम विस्फोट के बाद दिल्ली में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद आतंकवादी अपने उद्देश्य में सफल हो गए. इससे केंद्र का यह दावा खोखला साबित हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद आतंकवादी संगठन बिखर गए हैं. इसके विपरीत आतंकवादी तभी कोई बड़ी वारदात करते हैं, जब सरकार कमजोर पड़ने का दावा करती है.

—ब्रजेशचंद शर्मा, नई दिल्ली

निष्पक्ष जांच जरूरी

खास रपट 'लाजवाब कर देने वाले तथ्य' (15 जुलाई) में 'द हिंदू' द्वारा प्रकाशित तथ्यों ने सरकार और उसकी संसदीय समिति द्वारा पेश की गई सफाइयों को पूरी तरह नकार दिया. यदि सरकार अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहती है तो मामले की निष्पक्ष जांच करवानी होगी अन्यथा इसका प्रभाव आगामी चुनावों पर पड़े बिना नहीं रहेगा.

—कुरुणेश सिंह, बस्ती (उ.प्र.)

अविश्वसनीय छवि

सिनेमा स्तंभ में 'नायिका के नए तेवर' (15 जुलाई) पढ़कर लगा कि हिंदी फिल्मों का अगला दौर नारी प्रधान ही होगा. लेकिन ये फिल्में भी तभी लोकप्रिय होंगी जब उनकी कहानियां देश की समसामयिक समस्याओं से जुड़ी हों. हाथ में बंदूक या पिस्तौल पकड़ कर बदले की आग में झुलसती भारतीय नारी की छवि पेश करना अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है.

—नंदगोपाल मट्टड़, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

आशा की किरण

पंजाब के मलेरकोटला कस्बे में विभिन्न धर्मों के लोगों के आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना के बारे में ('जिसे रोशन खुदा करे': 15 जुलाई) पढ़कर सुखद अनुभूति हुई. ऐसा आभास हुआ कि आज के सांप्रदायिक तनाव के घोर अंधेरे में भी आशा की एक किरण जीवित है.

—राजन चोपड़ा, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुंदन-से निखरे

आवरण कथा 'राजा की अग्निपरीक्षा' (30 जून) पढ़ी. परीक्षा दरअसल राजा की नहीं, बल्कि राजीव गांधी के भविष्य की थी. वी.पी. सिंह की अग्निपरीक्षा तो तभी हो गई थी जब उन्होंने इस्तीफा देकर ईमानदारी का परिचय दिया था. भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधियों का भंडा फोड़ने के कारण उनके पास अपार जन समर्थन था, उसी के बल पर उन्होंने इलाहाबाद में अपनी छवि को निखारा है.

—पुरुषोत्तम गुप्ता, राजगढ़ (म.प्र.)

■ वी.पी. सिंह को सफल बनाकर जनता ने विपक्ष को भी अपना समर्थन देने की मंशा दिखाई है, बशर्ते वे एकजुट तो हों. विपक्ष अब भी यदि जनता की कसौटी पर खरा न उतरा तो उस पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा.

—कृष्णकुमार कमल, कपूरथला (पंजाब)

■ इंका कितनी भ्रष्ट और स्वार्थी हो गई है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि वी.पी. सिंह की ईमानदारी को चुनौती देने के लिए उसने स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री की छवि को भुनाने का प्रयत्न किया, उनके नारे उद्घोषित करवाए. जबकि उनकी मृत्यु के बाद हुए पांच संसदीय चुनावों में उनका कहीं नाम तक नहीं लिया गया था.

—के. राजन, इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ इलाहाबाद चुनाव परिणामों से विपक्ष को सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार वी.पी. सिंह को साझा उम्मीदवार के रूप में खड़ाकर जनता का समर्थन बटोरा है, अगले आम चुनाव में भी ऐसी ही एकता का प्रदर्शन करे तो कोई वजह नहीं कि जनता उसे विकल्प के रूप में न स्वीकारे.

—निमेष आसर, सिवनी (म.प्र.)

■ इस अग्निपरीक्षा में वी.पी. सिंह कुंदन बनकर निकले हैं. उनकी जीत से स्पष्ट हो गया है कि अब जनता को सचाई, ईमानदारी और देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाले नेतृत्व की जरूरत है.

—शिवेंद्र सिंह, गया (बिहार)

■ आवरण कथा में ही 'बसपा के बोल' पढ़कर गहरा आघात लगा. क्या स्वार्थ के वशीभूत कांशीराम इतिहास को नए सिरे से लिखने पर आमादा हैं? अच्छा हो कि देश में जातीयता के नाम पर वोट मांगना हमेशा के लिए बंद हो जाए और चुनाव प्रक्रिया संकीर्णता से ऊपर उठे.

—लाजपत राय आहूजा, नई दिल्ली

यथार्थ की कसौटी

'कसौटी' के अंतर्गत लेख 'ऐसे नहीं होगी शिक्षा में क्रांति' (30 जून) जानकारी भरा रहा. आंकड़ों को देखकर ही सरकार की अदूरदर्शिता का अंदाजा लगाया जा सकता है. नई शिक्षा नीति के रूप में राजीव गांधी के सपने साकार होते नहीं दिखते क्योंकि कोई भी नीति तभी सफल होती है जब उसमें यथार्थ का समावेश हो.

—प्रभाष चंद्र झा, पीरपैंती (बिहार)

■ सचाई यही है कि हमारे नेता नई शिक्षा-नीति, कंप्यूटरीकरण की तो बातें करते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि गांवों में स्कूलों की ब्लेकबोर्ड, बैठने के लिए टाट जैसी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पातीं. ऐसे में नई शिक्षा नीति द्वारा देश में क्रांति लाने का राग अलापना कितना हास्यास्पद और अवास्तविक लगता है.

—अनुराग श्रीवास्तव, होशंगाबाद (म.प्र.)

■ कसौटी के अंतिम अनुच्छेद में दिया गया सुझाव काफी उपयोगी है. वास्तव में शिक्षा नीति में नारेबाजी की नहीं, बल्कि बुद्धि विवेक और देश की जरूरत के हिसाब से नीति निर्धारित करने की आवश्यकता होती है. काश यह बात वर्तमान सरकार की समझ में भी आ जाती तो आज शिक्षा जगत का स्वरूप ही कुछ और होता.

—वेद प्रकाश पांडेय, बंगलूर (कर्नाटक)

समाधान ऐसे होगा

'आजकल' स्तंभ में 'मौका खोने में माहिर' (30 जून) में सरकार को इस बात के लिए दोषी ठहराया गया है कि उसने गुरद्वारा समिति से दुर्व्यवहार करके पंजाब में शांति का एक और मौका खो दिया, जबकि असलियत यह है कि गुरद्वारा समिति ने और खासतौर से तोहड़ा ने सरकार के लिए हमेशा परेशानियां ही खड़ी की हैं. सरकार ने मौका खोया तो है पर दूसरी तरह से. उसने 'ब्लैक थंडर' के तुरंत बाद गुरद्वारा एक्ट में संशोधन नहीं किया. पंजाब समस्या का समाधान शिरोमणि कमेटी भंग कर स्वर्ण मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने में ही है.

—रोहित परिहार, पंचकुला (हरियाणा)

भय को भुनाना

'कोचिंग केंद्र: धड़ल्ले से चलता धंधा' (30 जून) लेख वास्तविकता के काफी करीब लगा. आज हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस अफसर बनना चाहता है. उम्मीदवारों की संख्या हर साल बढ़ती जाने से उनमें एक असुरक्षा की भावना है, जिसे ये कोचिंग केंद्र वाले भुना रहे हैं. —हिमांशु कुमार सिंह, कानपुर (उ.प्र.)

■ इस धंधे के फलने-फूलने का कारण हमारी शिक्षा प्रणाली ही है, जिसमें रोजगार दिलाने की क्षमता का अभाव है. यदि शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जाए, या तब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्कूल-कॉलेजों में ही कराई जाए तो प्राइवेट कोचिंग केंद्रों का एकाधिकार तो समाप्त होगा ही, गरीब किंतु प्रतिभावान छात्र भी लाभान्वित होंगे.

—योगेश कुमार दूबे, इंदौर (म.प्र.)

अधूरी श्रद्धांजलि

राजकूपर पर लेख 'नीली आंखों के सपने और सचाइयां' (30 जून) पढ़कर निराशा ही हुई. 'इंडिया टुडे' जैसी सामयिक पत्रिका से हम हर विषय पर विस्तृत सामग्री की अपेक्षा करते हैं, जो इस लेख में नहीं मिली.

—हर्ष कुमार, मुजफ्फरनगर (म.प्र.)

■ यह सही है कि राजकपूर की मौत से सिने जगत का एक प्रतिभावान निर्देशक उठ गया. लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि उनके बिना सिने जगत अधूरा रहेगा. कुछ वर्षों से जैसी फिल्में वे बना रहे थे उन्हें पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा नही जा सकता. अपने नाम और प्रभाव से तारिकाओं से 'कुछ भी' करा लेने का दुस्साह राजकपूर में ही था. —उमेश प्रसाद, पटना (बिहार)

इस्लामी असमंजस

अफगान नेता हिकमतियार से बातचीत 'चुनी हुई सरकार ही चाहिए' (30 जून) अच्छी लगी. जिस देश और समाज में समय के अनुरूप नई बातें अपनाने और पुरानी को छोड़ने का गुण नहीं होता. वह अंतर्द्वंद्व, आर्थिक असमंजस में फंसकर शांति खो देता है. इस नजरिये से इस्लाम के पैमानों पर पुनः विवेचन जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम देशों के हालात काफी बदतर हैं.

—स्वामी कार्तिक भारती, कानपुर (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya S... eGa...

डायमंड पॉकेट बुक्स में

पेश करते हैं –
एक महान उपन्यासकार

विक्की आनन्द

का नया जासूसी उपन्यास

बुद्ध

6/-

- लेखक का दावा है कि यह उपन्यास आपको अवश्य पसंद आयेगा।
- एक नई किस्म के जासूसी उपन्यासों की परम्परा इस उपन्यास से शुरू होगी।
- विक्की आनन्द के उपन्यासों में रहस्य, रोमांच और इन्वेस्टीगेशन का ऐसा अनूठा समन्वय है कि आप उपन्यास को एक ही बार में पूरा पढ़े बिना नहीं छोड़ पायेंगे।

डायमंड पॉकेट बुक्स प्रा.लि.
2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोषी मां बाप भी

'दानवी जुनून का फैसला दायरा' (30 जून) पढ़कर लगा कि संविधान में स्त्री-पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बावजूद समाज के तौर-तरीकों में कोई अंतर नहीं आया है. आपने ठीक ही लिखा है कि इन हत्याओं के लिए लड़की के माता-पिता भी बराबर के जिम्मेदार हैं.

—**महिमा मिश्रा,** लखनऊ (उ.प्र.)

■ इस कुरीति को बढ़ावा देने में ज्यादा दोष लड़की के माता-पिता का ही है, जो अपनी बेटी की शादी अपने से ज्यादा संपन्न घरों में करना चाहते हैं, उस संपन्नता की कसौटी होती है—पैसा और टी.वी. और वीसीआर आदि से भरापूरा घर, भले ही ससुराल वालों का शिक्षा, संस्कार और नैतिक मूल्यों से दूर का भी वास्ता न हो.

—**रमेश कुमार साहू,** पानीतोला (असम)

सांठगांठ का धंधा

'तस्करी की स्वर्णरेखा' (30 जून) पढ़कर कोई आश्चर्य नहीं हुआ. वस्तुतः उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि नेपाल की सीमा से सटे बिहार के उत्तरी जिलो में भी विदेशी सामान की खरीद-बिक्री धड़ल्ले से होती है. व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं पर न तो नेपाल का और न ही भारत का चुंगी विभाग रोकथाम करता है, क्योंकि दुकानदारों से उनकी सांठगांठ रहती है.

—**प्रभात कुमार सिन्हा,** मधुबनी (बिहार)

मानवतावादी दृष्टिकोण

'समाजसेवा से समाधि तक' रिपोर्ट (30 जून) पढ़ी. दक्षिण भारत के मठाधीशों ने अपनी धर्मांधता त्यागकर समानता और मानवतावादी जो दृष्टिकोण अपनाया है वह बहुत प्रशंसनीय है. मठाधीश, धार्मिक विद्वान यदि निश्चय कर लें तो वे छुआछूत ही नहीं, दूसरी भी कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने में योगदान दे सकते हैं.

—**बिंदिया अरविंद,** भोपाल (म.प्र.)

दुखद सच

रहन-सहन के अंतर्गत 'बीवी को बेचने की मजबूरी' (30 जून) अंदर तक हिला गई. सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब इस स्थिति में रचनात्मक परिवर्तन ला सकने की क्षमता रखने वाले नेताओं की ढिठाई यथावत बनी रहती है. मुख्यमंत्री व तहसीलदार द्वारा तथ्यों को झुठला कर सच पर परदा डालने की असफल कोशिश तो छलावा ही लगती है.

—**अरुण बोथरा,** फरीदाबाद (हरियाणा)

अव्यावहारिक विधेयक

'विधि-विधान' स्तंभ के अंतर्गत 'किराया नियंत्रण विधेयक' (30 जून) लेख से यह साबित होता है कि केंद्र सरकार बड़े मकान मालिकों के हितों को किस तरह सुरक्षित रखती है. इस किस्म के अव्यावहारिक विधेयक लाने से पहले अगर हमारी सरकार देश के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखती या इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस प्रारूप के रूप में प्रस्तुत करती तो यह निहायत अच्छा होता.

—**एस.पी. दवे,** अमृतसर (पंजाब)

जरूरी जो है प्रचार

'चप्पे-चप्पे पर चस्पां प्रचार' (30 जून) रिपोर्ट में आपने सही स्थिति पर प्रकाश डाला है. व्यवसाय जगत में बढ़ती प्रतियोगिता के कारण विज्ञापन का महत्व इतना बढ़ गया है कि उत्पादक आज विज्ञापन को उत्पादन का ही एक हिस्सा समझते हैं. और समझें भी क्यों नहीं विज्ञापन के बिना उत्पादन का बाजार में बिकना नामुमकिन ही है.

—**आनंद लोहारुका,** दरभंगा (बिहार)

स्पष्टीकरण

इंडिया टुडे, 15 जनवरी 1987 के अंक में प्रकाशित लेख 'बच गई अनमोल निधि' में लिखा गया है कि "इस साल मई-जून में टोंक की ही जिला अदालत में कब्जे से सात साल पहले चुराया गया एक शिवलिंग एक बाबा और एक वकील की अर्जी पर छोड़ दिया गया. वकील भी कौन-सा जो इसी शिवलिंग के कथित चोरों की पैरवी कर रहा था." यहां स्पष्ट किया जाता है कि एडवोकेट गिरधारी गोपाल श्रीवास्तव और भागचंद जैन के आवेदन पर शिवलिंग सुपुर्दारी में नहीं दिया गया. दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के एक अफसर के आवेदन पर अदालत ने शिवलिंग उनकी सुपुर्दगी में दिया था. यदि उक्त प्रकाशन से इन वकीलों की भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उसका हमें खेद है.

—**संपादक**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

चक्के की चुनौतियां

सरकार ने अर्थनीति संबंधी जो घोषणाएं इधर की हैं उनसे लगता है कि वह उद्योग नीति को उदार बनाने और मठों वाली जड़ता में जकड़े भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धा का स्वाद चखाने की अपनी नीति जारी रखेगी. यह आश्वस्त करने वाली बात लगती है. राजीव सरकार के चार वर्षों के शासन की गिनी-चुनी उपलब्धियों में इसे भी शुमार किया जा सकता है. पिछले दो वर्षों से सरकार जिन फजीहतों का सामना कर रही थी उनके मद्देनजर तो यही लग रहा था कि कहीं वह लोकलुभावन उपायों के लिए अपनी अर्थनीति उलट ही न दे. लेकिन पिछले महीने उसने नाटकीय घोषणा की कि पिछड़े इलाकों में कई तरह के उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी. फिर पिछले पखवाड़े इस घोषणा के संदर्भ में उसने जो कार्रवाइयां की उनसे साफ हो गया है कि वह अपनी मान्यताओं पर कायम है और उद्योग जगत की जरूरतों को भली-भांति पहचानती है.

रेखाचित्र: अजीत नैनन

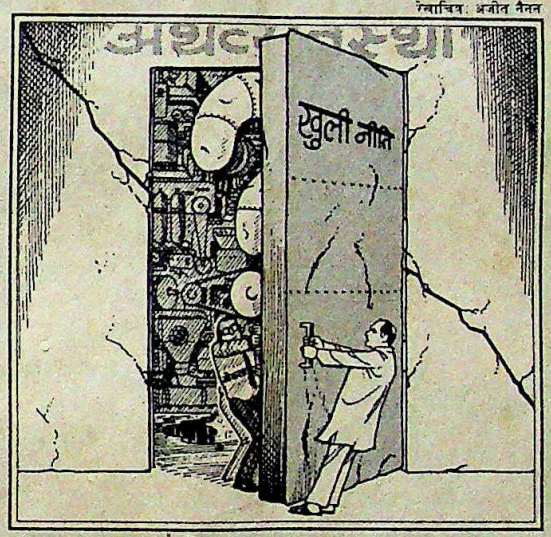

पिछले चार वर्षों से जो फेर-बदल किए जाते रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं. उनमें रेगन और थैचर की सैद्धांतिकता या व्यापकता का तत्व भले न हो मगर भारतीय संदर्भों और सीमाओं में उन्होंने एक तरह से भारतीय उद्योग की नई दिशा तय कर दी है. लाइसेंस नीति को उदार बनाने की बात हो या नए पूंजी निवेश की सीमाओं का निर्धारण या एकाधिकार कानून में सुधार की बात, हर मामले में सरकार ने एक निश्चित मान्यता और विश्वास का परिचय दिया है. 'आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण', 'निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र' जैसे पुराने मुहावरे भूलकर नए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं जैसे—'तात्कालिक प्रासंगिकता', 'प्रतिस्पर्धा के जरिये कार्यकुशलता', 'तकनीकी विकास' आदि-आदि.

नई नीति के नतीजे अच्छे रहे हैं यह मानने के पर्याप्त कारण भी हैं. कुछ क्षेत्रों में पूंजी निवेश के केंद्रित होने से यह जरूर हुआ कि मांग की तुलना में उत्पादन क्षमता बढ़ी है और मुनाफे में अस्थायी गिरावट आई है. लेकिन कुल मिलाकर गहमागहमी का आलम है. लागत घटाने, पूंजी निवेश बढ़ाने और नई तकनीक के लिए जोड़तोड़ जारी है. सूखा वर्ष और शेयर बाजार में गिरावट खत्म होने के साथ उद्योग जगत में लौटी जान के मद्देनजर सरकार को चाहिए कि वह उसे हाथ-पैर फैलाने की थोड़ी और जगह दे.

लेकिन साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि नई नीति की सचमुच क्या उपलब्धियां रही हैं. उत्पादन लागत घटाकर एक निश्चित सीमा पर लाने की अर्थव्यवस्था क्या विकसित हो रही है? नई नीति के चलते जिन क्षेत्रों में गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें दूर करना होगा. नई परियोजनाओं में विदेशी मुद्रा के भारी निवेश की शिकायतें सुनी जाती हैं. उधर कुछ औद्योगिक हलकों में यह धारणा है कि बदलाव की जितनी कोशिशें होती हैं उनका हश्र सिर्फ यथास्थिति में ही होता है. सो अगर सचमुच कुछ हासिल करना है तो इन तमाम मुद्दों से सीधे-सीधे निबटना होगा.

और फिर अभी तो यही निश्चित नहीं है कि जिन कारणों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च लागत वाली बनी हुई है उनका निबटारा हो पाया है या नहीं. करों के ढांचे की बात हो या उत्पादन-लागत संतुलन या कच्चे माल की कीमत की बात हो, तमाम मोर्चों पर प्रगति आंशिक ही रही है. रुपए के अवमूल्यन से भी सीमेंट, खाद, इस्पात और कई उपभोक्ता वस्तुएं विदेशी बाजार में सस्ती नहीं हो पाईं. करों में छूट, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और तगड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद पोलिएस्टर का भी वही हाल है.

दूसरी समस्या है औद्योगिक इकाइयों के 'बीमार' पड़ने की और ऐसी इकाइयों को बंद करके 'छुट्टी' पाने के अधिकार की बढ़ती मांग की. ये दोनों इस बात के संकेत हैं कि देसी बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी तेज हुई है. साफ है कि इन मामलों से निबटने में नई नीति बहुत कारगर नहीं रही है. केंद्र और राज्य स्तर पर जिस तरह के दबाव और नियंत्रण काम करते हैं उनके कारण बीमार कारखानों से 'छुट्टी' पाने का अधिकार न के बराबर ही है. बैंकों और वित्तीय संस्थानों की कथित निगरानी के बावजूद 'बीमारी' रोकने की कार्रवाई शायद ही समय पर हो पाती है. बीमार इकाइयां अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा करती हैं. बढ़ती होड़ के माहौल में ऐसी इकाइयों का बने रहना अच्छा लक्षण नहीं है.

इससे भी बड़ी समस्या तो यह है कि लोग यह मानने को तैयार नहीं कि तमाम गतिविधियों और नियम-कानूनों को सरल बनाने की कोशिशों के बावजूद कहीं कुछ बदला भी है. कारखाने के लिए लाइसेंस तो तुरत-फुरत मिल सकता है लेकिन बाद में कारखाना लगाने में कई बाधाएं आती हैं. दरअसल कुछ बड़ी परियोजनाएं तो सरकारी अनिर्णय के कारण ही लटकी पड़ी हैं. दो उदाहरण तो सामने हैं—हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स और पेप्सी कोला के प्रस्ताव के. नौकरशाही, अपनी सुस्त रफ्तार से काम करती ही है. दरबार लगवाने की परंपरा कायम है. व्यवसायी और उद्योगपति महा-शक्तिवान नौकरशाहों का मुंह जोहे रहते ही हैं. खुली अर्थव्यवस्था वाले देश का कोई व्यक्ति भारत में आ जाए तो उसे यही लगेगा कि सच्चे अर्थों में यहां कोई बदलाव नहीं आया है.

फिर भी कहा जा सकता है कि यही वह क्षेत्र है जिसमें राजीव सरकार ने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने की तर्कसंगत नीति अपनाई है. बदलाव निश्चित तौर पर धीमी गति से हुआ है, और जरूरत बहुत कुछ करने की है. लेकिन भारत में फैसले करने की जो प्रक्रिया है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक है. इसलिए उम्मीद है सरकार इस दिशा में आगे अपेक्षित प्रयासों के लिए सक्रिय होगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपकी चहेती पत्रिका
आपके दरवाज़े पर
न खरीदने का झंझट...
न खत्म होने का डर

इस सुविधा का लाभ उठाइए.
आपनी चहेती इंडिया टुडे
घर बैठे – नियमित पाइए.
न खरीदने जाने की ज़रूरत...
न अंक खत्म होने का डर,
इंडिया टुडे
समय से पहुंच जाए आपके घर !

बस कूपन भर कर भेज दीजिए,
देर मत कीजिए !

नाम _____

डाक पता _____

मूल्य : वार्षिक रु. 120/-
भुगतान का माध्यम – चैक/मनीआर्डर/डिमाड ड्राफ्ट
कृपया चैक निम्नलिखित नाम पर बनाएं और इस पते पर भेजें
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि
सबस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट गौमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. नं. 69, दिल्ली मथुरा रोड,
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

रविशंकर, इंडियन एक्सप्रेस

● विरोधी दलों के अध्यक्ष ही विपक्षी एकता के दुश्मन हैं और कांग्रेस को फायदा पहुंचाना चाहते हैं. अगर विपक्षी एकता होगी तो एक पार्टी बनेगी और उसका एक ही अध्यक्ष होगा, तो बाकी 11 की नौकरी चली जाएगी. ■ **देवीलाल,** *रविवार*

● विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी. लेकिन अफसोस कि यह पद खाली नहीं है. ■ **के.के. तिवारी,** *संडे मेल*

● मैं प्रधानमंत्री बन गया तो अनिष्ट ही हुआ मानिए. इसलिए इस सवाल पर बहस यहीं खत्म हो तो बेहतर. ■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *टाइम्स ऑफ इंडिया*

● राष्ट्रीय राजनीति में आने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता. ■ **रामकृष्ण हेगड़े,** *ऑनलुकर*

● हमने हेगड़े को पूरी तरह चित कर दिया है. ■ **एच.डी. देवगौडा,** *नई दुनिया*

● मैंने वी.पी. सिंह से कह दिया कि अगर एक भी मुस्लिम वोट चाहते हैं आप, तो आरिफ को चुनाव मंच पर आने मत दीजिएगा. ■ **सैयद शहाबुद्दीन,** *संडे ऑब्जर्वर*

● मतदान के एक दिन पहले भी सिर्फ 50 हजार रुपए का जुगाड़ हो जाता तो सारी सरकारी धांधलियों के बावजूद मैं 50 हजार वोटों से ज्यादा से जीत जाता. ■ **भीम सिंह,** *जनसत्ता*

● पार्टी के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि लोग (राजनीति में) जन्म लेते ही विधायक बन जाना चाहते हैं और विधायक बनते ही मंत्री. ■ **बीरबहादुर सिंह,** *इलस्ट्रेटेड वीकली*

● हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप आधा दिन के क्रिकेट मैच देखें. ■ **अशोक मांकड़,** *दैनिक जागरण*

● मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहूंगा कि पी.टी. उषा को इस ढंग से प्रशिक्षण नहीं मिला है कि वह ओलंपिक के 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में पहुंच सके. ■ **मिलखा सिंह,** *पंजाब केसरी*

● लोग यथार्थवादी फिल्में देखना नहीं चाहते. उन्हें तो गांव की लड़की भी सिल्क की चोली पहने, नेल पॉलिश लगाए दिखनी चाहिए... वे ग्लैमर देखना चाहते हैं, कला नहीं. ■ **अशोक कुमार,** *माधुरी*

● मेरी नींद इतनी कच्ची नहीं कि सोनम के आने से उड़ जाए. ■ **श्रीदेवी,** *दैनिक जागरण*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नेकनीयती का तकाजा

● पंजाब में आतंकवाद को पाकिस्तान से मिल रही शह को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी अब एक जटिल दौर में पहुंच गई है. पिछले दिनों नई दिल्ली में दोनों देशों की वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी पक्ष को नक्शों और दस्तावेजों का एक मोटा पुलिंदा थमाया. इसमें पाकिस्तान स्थित उन 22 शिविरों का ब्यौरा था जहां सिख आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है. प्रशिक्षण देने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम और वहां के शहरों में रहने वाले 20 कुख्यात आतंकवादियों के नाम-पते भी इसमें दिए हुए थे.

लेकिन पाकिस्तानी पक्ष ने इन आरोपों का खंडन कर दिया और अपनी नेकनीयती का बखान करने लगा. इस पर भारतीय पक्ष ने जाल बिछाया और चारा डाला. उसने कहा कि यदि इस्लामाबाद अपनी नेकनीयती जाहिर करना चाहता है तो वह उन आतंकवादियों में से कुछ को भारत भेज दे. जिनके नाम और पते दस्तावेज में दिए गए हैं. लेकिन

पाकिस्तानी पक्ष इस फंदे में नहीं आया. अब भारतीय पक्ष ने दूसरा पांसा फेंका. उसने पाकिस्तानी पक्ष से कहा कि कुछ नहीं तो 20 आतंकवादियों में से सिर्फ एक को तो वह वापस भेजे.

भारतीय विदेश विभाग इस बातचीत के नतीजे के प्रति ज्यादा आशान्वित नहीं है. लेकिन उसे लगता है कि पाकिस्तान किसी एक आतंकवादी को भेजकर नेकनीयती का संकेत तो दे ही सकता है.

जिम्मेदारी की बात

● गोपी अरोड़ा वैसे तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री की ओर से दूसरे कई काम भी करते हैं जो

कार्टून: अजीत नैनन

आमतौर पर नाजुक राजनैतिक और कूटनीतिक मामलों से जुड़े होते हैं. पिछले पखवाड़े उन्होंने अपनी यही परिचित भूमिका निभाई. उन्हें जो काम सौंपा गया था उसमें कूटनीतिक और राजनैतिक दोनों तत्व मौजूद थे. जगह, जहां काम को अंजाम देना था वह थी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा. और काम था वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी को यह सूचित करना कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब नहीं रहे, कि उन्हें उनकी गैर-मौजूदगी में ही उत्तर प्रदेश इंका विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. उन्हें यह सूचना उनके लंदन से लौटते ही हवाई अड्डे पर देनी थी.

इस विशेष काम के लिए अरोड़ा का चुनाव तर्कसंगत था. वे उत्तर प्रदेश के ही हैं और उन्होंने तिवारी से बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं. तिवारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापस जाने के लिए अनिच्छुक थे. लिहाजा महसूस किया गया कि अरोड़ा ही तिवारी को यह समझा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंका की नैया उबारने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति वे ही हैं. सो अरोड़ा हवाई अड्डे पहुंच गए और साथ में दूरदर्शन की एक कैमरा टीम भी ले गए. दरअसल, दूरदर्शन टीम को साथ ले जाने का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि तिवारी खुद ही दूरदर्शन कैमरे के सामने नई जिम्मेदारी संभाल लेने की बात कहें.

घरवालियों का मामला

● नई दिल्ली में थलसेनाध्यक्ष का सरकारी बंगला 'सेना भवन' अभी भी खाली है. भला हो पूर्व और वर्तमान थलसेनाध्यक्षों की पत्नियों का! वर्तमान थलसेनाध्यक्ष जनरल बी.एन. शर्मा राजपूताना राइफल्स के मेस में रह रहे हैं क्योंकि जनरल के. सुंदरजी अवकाश ग्रहण के बाद सेना भवन का अधिकतर फर्नीचर और साज-सामान अपने साथ लेते गए. (सूत्रों का कहना है कि उनकी पत्नी ले गईं).

खैर, सेना भवन में जब उनकी जगह पर्याप्त फर्नीचर और साज-सामान आ गया, तो रक्षा मंत्रालय के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई. थलसेनाध्यक्ष शर्मा की पत्नी

की फरमाइश है कि सेना भवन के शयनकक्ष के बगल में एक दूसरा ड्रेसिंग कक्ष बनवाया जाए, तभी वे वहां बसेंगी. वे व्यस्त महिला हैं और उन्हें भी उसी समय तैयार होना पड़ता है जिस समय उनके पति बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं. जनरल शर्मा ड्रेसिंग कक्ष का इस्तेमाल पहले करते हैं.

शिष्टाचार या सजा

● प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विदेश दौरों के कारण सबसे ज्यादा परेशान होते हैं शिष्टाचार अधिकारी. प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हर आदमी धक्का-मुक्की करके आगे आना चाहता है. लिहाजा इन अधिकारियों को स्वागत के वास्ते खड़े लोगों में से प्रमुख लोगों को अलग करने के लिए खासी मेहनत

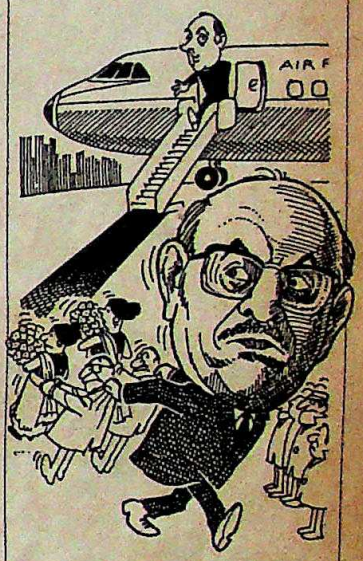

करनी पड़ती है. राजीव की पिछली विदेश यात्रा के दौरान उनके एअर इंडिया जंबो पर सवार शिष्टाचार अधिकारियों के सामने मुसीबत उस समय पैदा हो गई जब विमान न्यूयॉर्क के जे.एफ. केनेडी हवाई अड्डे पर उतरा. चूंकि राजीव वहां की राजकीय यात्रा पर नहीं थे, इसलिए उनके स्वागत के लिए राजदूत प्रताप कौल की अगुआई में मुख्य रूप से भारतीय दूतावास के कर्मचारी और प्रमुख भारतीय जुटे हुए थे.

समस्या यह थी कि प्रधानमंत्री को माला कौन पहनाए और गुलदस्ता कौन भेंट करे. शिष्टाचार के मुताबिक ये काम राजदूत की पत्नी को करने थे. लेकिन वे मौजूद नहीं थीं. इसलिए संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सी.आर. घरेखां और न्यूयॉर्क में वाणिज्यदूत पीटर नजारय की पत्नियां अगली कतार में खड़ी की गईं. लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों को यह जंच नहीं रहा था. राजीव विमान से उतरकर नीचे आते उससे पहले ही इन दोनों महिलाओं को धकेलकर एकदम पीछे कर दिया गया.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऋणमुक्ति का रास्ता

■ उधार ने चुकाने वालों से निबटने के लिए आम तौर पर या तो हाथापाई किए जाने की परंपरा है या फिर अदालत की मदद लेने की. लेकिन पिछले दिनों हरियाणा के नीलोखेड़ी कस्बे के एक दुकान-

दार ने जो तरीका अपनाया उसने लोगों को गप्पबाजी के लिए अच्छा-खासा मसाला जुटा दिया. इस दुकानदार के एक सरकारी कर्मचारी पर 600 रुपए उधार थे जिन्हें वसूल करने के लिए वह चक्कर काटते-काटते तंग आ चुका था.

दुकानदार ने पिछले पखवाड़े उसके घर पर फिर से दस्तक दी. इस बार तकाजे और बहाने का दौर जल्दी ही तू-तू मैं-मैं तक जा पहुंचा. देखते-देखते मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए. दुकानदार पैसे लिए बिना जाने को तैयार नहीं था और देनदार का टका-सा जवाब था कि "पैसे नहीं हैं तो क्या भीख मांग-कर तुम्हारा भुगतान करूं?" रोज-रोज की चखचख से परेशान दुकान-दार को इस दलील में आशा की किरण दिखाई दी. उसने भीड़ की मौजूदगी में शर्त रख दी कि अगर बाबू साहब भीख मांगकर दिखा दें तो वह कर्जा वापस नहीं मांगेगा. बाबू जी को कर्जे से मुक्ति का रास्ता दिख गया. वे तुरंत घर के भीतर गए और कटोरा लेकर भीड़ के सामने हाजिर हो गए. कटोरे और बाबू जी ने चक्कर लगाया और देखते-देखते कटोरे में ढाई रुपए जमा हो गए जिसमें दुकान-दार के दिए हुए सिक्के भी थे. शर्त पूरी हुई और बाबू जी को उधार से मुक्ति के अलावा ढाई रुपए की आमदनी भी हो गई.

'अखाड़ेबाजों' पर लाठी

■ प्रदर्शनों के फैशनों और दंगे-बाजी की परंपरा का एक परि-णाम यह है कि हिंदुस्तानी पुलिस को आए दिन लाठियां भांजने का मौका मिलता रहता है. हालांकि जलसे-जुलूस नियंत्रित करने और प्रदर्शनकारियों की खोपड़ी पर अपनी लाठियों का कमाल दिखाने का यह मौका देश के लगभग हर शहर, कस्बे में पुलिस को कभी-कभार मिलता रहता है पर देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस को तो यह सौभाग्य आए दिन ही मिलता रहता है. लेकिन पिछले पखवाड़े पुरानी दिल्ली के कुछ पुलिसवालों को जिस तरह के शरारती तत्वों से निबटने की जिम्मेदारी सौंपी गई वह उनके लिए सिरदर्द साबित हुआ.

एक सुबह हौजकाजी इलाके के लोग अपने घरों से काम के लिए निकले ही थे कि सड़क पर यातायात जाम देखकर दंग रह गए. इस जाम का कारण कोई धार्मिक जुलूस या राजनैतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि कुत्तों के दो दल थे, जिन्होंने सड़क को अखाड़ा बनाने का फैसला कर लिया था. कुत्तों को हटाने के लिए पहले तो कारों, स्कूटरों के हॉर्न और साइकिलों की घंटियों का इस्तेमाल किया गया. पानी की बाल्टियों को भी आजमाया गया. आखिरकार मामला हाथ से निकलता देख पुलिस को फोन

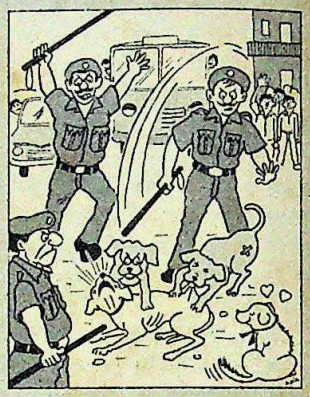

किया गया. पुलिस ने सक्रियता दिखाई और देखते-ही-देखते पुलिस के तीन जवान लाठियों समेत कार्-वाई के लिए हाजिर हो गए. जवानों ने लाठीचार्ज किया, तब कहीं जाकर कुत्तों ने मैदान छोड़ा.

सिर मुंडाते ओले

■ पंजाब पुलिस ने पिछले पख-वाड़े 'भावी' आतंकवादियों के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया जिसके सदस्य आतंकवाद की आड़ में लूटमार को 'कैरियर' के तौर पर अपनाने की फिराक में थे. 16

और 22 साल की उम्र वाले ये चार आतंकवादी इस नए कैरियर के प्रति इतने गंभीर थे कि उन्होंने न केवल नकली बंदूकें तैयार कीं बल्कि लूटमार की बाकायदा रिह-र्सल का भी इंतजाम कर लिया. मगर वाह-री किस्मत! बेचारे 'आतंकवादी' रिहर्सल के दौरान ही धर लिए गए.

समाचारों के अनुसार मजीठा इलाके के इन युवकों ने यह तय किया कि लूट के असली 'मिशन' पर निकलने से पहले अपने ही घरों में इसकी रिहर्सल कर ली जाए ताकि असली 'मिशन' की काम-याबी पक्की हो जाए. इस काम के लिए तीन नकली बंदूकें बनाई गईं और गिरोह के नेता ने बाकी सदस्यों को अगले बुधवार के दिन अपने घर पर 'लूटमार' करने का निम-त्रण दिया. पर उत्साही साथी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाए और उन्होंने रविवार की रात को अपने नेता के घर धावा बोल दिया. दुर्भाग्य से उनका नेता उस समय घर पर नहीं था. घरवालों ने आतंकवादियों को देखते ही शोर मचा दिया और बात की बात में मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए. आतंक-वादियों ने नकली बंदूकों से उन्हें डराने की कोशिश की पर लोगों ने उन्हें धर-दबोचा और अच्छी-खासी ठुकाई के बाद उन्हें पुलिस के हाथ में सौंप दिया.

ठग 'सिपाही'

■ ठगों की बिरादरी आए दिन ऐसे-ऐसे हथकंडे ढूंढ़ निकालती है कि होशियार लोग भी चक्कर खा जाएं. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक कस्बे में तीन ठगों ने एक दुकानदार को एक नए अंदाज में अपनी इस कला का मजा चखाया.

ठगों में से दो ने पुलिस की वर्दी पहनी और तीसरे को हथकड़ी पहनाकर एक मुलजिम की तरह एक दुकान में ले गए. और लाला जी से मुलजिम को पहचानने को कहा लेकिन वे उसे जानते तभी तो पहचानते! मगर मुलजिम ने तुरंत मान लिया कि वह लाला जी को जानता है. 'सिपाहियों' ने उन्हें बताया कि उक्त मुलजिम को जाली नोटों के धंधे में पकड़ा गया है और उसने बयान में लाला जी का नाम भी लिया है. अब बेचारे लाला जी को काटो तो खून नहीं. उन्होंने 'पुलिसवालों' को बहुतेरा समझाने की कोशिश की कि उनका उस आदमी से कोई वास्ता नहीं है पर 'पुलिसवालों' की जिद थी कि वे उनके साथ थाने चलें. बेचारे लाला जी किसी भी हाल में एक अपराधी के रूप में थाने जाने को तैयार नहीं थे. आखिर 'सिपाहियों' ने उनकी तकलीफ को समझते हुए यह प्रस्ताव रखा कि अगर उन्हें पांच हजार रुपए दे दिए जाएं तो लाला जी का नाम मामले से

निकाल दिया जाएगा. आखिर सौदा दो हजार में तय हुआ. इधर 'सिपाही' अपनी सफलता पर संतु-ष्ट थे, उधर लाला जी इस मुसी-बत से छूटकर राहत महसूस कर रहे थे. —संकलन: विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनिश्चय और आतंक

मौत के मातम ने बीते पखवाड़े को गहरी उदासी के गर्त में धकेल दिया. झील में गिरी रेलगाड़ी के मलबे, गहरे पानी से निकाले जाते शवों और हाहाकार करते उनके स्वजनों ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया. बड़े-बड़ों के ठंडे और रस्मी शोक संदेश गूंजते रहे. क्विलोन की अष्टमुडी झील में हुई रेल दुर्घटना के दृश्य जितने भयावह थे, दुर्घटना के पीछे छिपे संकेत उससे कहीं भयावह हैं. रस्मी सहानुभूतियों से उसकी तल्खी कम नहीं हो पाएगी. दुर्घटना का कारण: रेल पटरियों की कुव्यवस्था, यानी दुनिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था सबसे खतरनाक भी है.

लेकिन कुल मिलाकर संकेत यही है कि हम मानो किसी अनिश्चित राह के राही हों और बीता पखवाड़ा उस राह का एक पड़ाव भर था—अज्ञात की ओर आखिरी सफर शुरू करने के पहले दम लेने का एक छोटा-सा मौका.

अपने खुफिया संगठन 'रॉ' के प्रतिनिधियों के संकेत पर केंद्र सरकार ने तमिल ईलम मुक्ति चीतों से समझौते की घोषणा तो कर दी लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि कुछ जल्दबाजी हो गई है. बहरहाल, जाफना में जलजला जारी है. चीतों की अपेक्षाओं और भारत सरकार के आश्वासनों में अभी भी भारी अंतर है. फिर भी एक कामचलाऊ अंतरिम समझौते की संभावना कायम है, भले ही इसके सत्व और स्थायित्व के बारे में पहले से कुछ बता पाना संभव न हो.

इसी तरह एक और अलगाववादी आंदोलन—दार्जिलिंग की पहाड़ियों में जारी गोरखालैंड आंदोलन—समझौते की ओर बढ़ते-बढ़ते जैसे अचानक उस रास्ते से फिसल गया. इसके नेता सुभाष घीसिंग ने जब घोषणा की कि अब और हिंसा नहीं होगी तो लगा कि आंदोलन खत्म ही होने वाला है. मगर आगजनी और हत्याएं जिस तरह जारी रहीं उनसे शांति की संभावनाएं फिर ओझल हो गईं. उधर राजनीति के मंच पर भी लगा जैसे किसी अवतार की प्रतीक्षा की जाती रही. कांग्रेस कार्यकारिणी अहम फैसले करने के लिए इकट्ठा हुई मगर अंततः यही लगा कि बहुत कुछ हो नहीं पाया. पुराने कांग्रेसियों को वापस बुलाने की चर्चा भी चली मगर शायद उन्हें यह बहुत आकर्षक पेशकश नहीं लगी.

विपक्षी पार्टियों ने आगे की रणनीति के मद्देनजर एक होने या अलग-अलग रहने का फैसला करने के लिए एक बैठक बुलाना तय किया. मगर जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर ने इससे अलग रहने का बहाना बना लिया. यानी नतीजा अनिश्चित ही रहेगा. इसी तरह अनिश्चित बना हुआ है वी.पी. सिंह और उनके जनमोर्चा का भविष्य. उन पर 'स्वांग' छोड़कर राजनैतिक पार्टी का बिल्ला लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है.

इसी तरह अधर में लटका है कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े का भविष्य. अपनी पार्टी के असंतुष्टों, अपनी ही पार्टी के आलाकमान और कांग्रेस की साजिशों के कारण यह योद्धा एक बार फिर जैसे निर्णायक संघर्ष में उलझा हुआ दिखा. असंतुष्टों के खिलाफ कार्रवाई ने उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत तो की है लेकिन संकट के बादल अभी छंटे नहीं हैं.

अनिश्चितता तो जैसे दुर्निवार हो गई है. केंद्र सरकार ने यह तो संकेत दिया कि पंजाब समस्या के समाधान की उसने नई योजना बनाई है लेकिन उसका ब्यौरा देने से इनकार कर दिया. उद्योग नीति में उदारता की राह पर चलने का संकेत तो उसने दिया मगर उलझन में भी वह दिखी.

और प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक बार फिर विदेश के अपने निश्चित पड़ावों की ओर चल पड़े. राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन पहले ही एअर इंडिया का एक जंबो लेकर मॉस्को चले गए. यानी एअर इंडिया से यात्रा का टिकट खरीद चुके बाकी यात्री अनिश्चय में पड़े रहें. ऐसे में शायद यह खुलासा करने की जरूरत नहीं कि एअर इंडिया का असली 'महाराजा' कौन है.

—दिलीप बॉब

कार्टून: अजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

भारी पड़ता भितरघात

नेतृत्व की शह पर बागियों की मनमानी से हेगड़े परेशान

मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के लिए पार्टी की राज्य इकाई में असंतुष्टों के विद्रोह का खतरा कोई नई बात नहीं है. पर इस बार एक खास फर्क भी है. असंतुष्टों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह से खुली शह मिली. इस भारी संकट का सामना हेगड़े ने पूरी मुस्तैदी से किया. पर अब यह लड़ाई बहुत गंभीर दौर में प्रवेश कर गई है. एक रिपोर्ट:

एक ओर तो असंतुष्टों ने तीन महीने से उनकी नींद हराम कर रखी थी, दूसरी ओर उनकी अपनी जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी ओर से जैसे आंखें मूंद रखी थीं. मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने इस विकट परिस्थिति से उबरने के लिए अंततः पिछले पखवाड़े कार्रवाई की. मझोले 'कद और वजन' के कुछ बागियों को उन्होंने पार्टी से निलंबित कर दिया. इस उम्मीद में कि इससे बाकियों को सबक मिलेगा. छह बागी विधायकों को निलंबित करने के बाद हेगड़े ने साफ-साफ कहा, "चंद लोगों की मनमानी मैं ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था."

हेगड़े ने यह आक्रामक कार्रवाई 3 जुलाई को विधान परिषद चुनावों के तीसरे और अंतिम दौर की समाप्ति के बाद की. इन चुनावों से यह साबित हो गया कि असंतुष्ट गुट की ताकत को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जा रहा है (देखें बॉक्स). बहरहाल, इससे पहले भी परीक्षण के तौर पर हेगड़े 28 जून को पार्टी के चार सदस्यों को, जिनमें दो असंतुष्ट भी शामिल थे, निलंबित कर चुके थे. बाद में जिला और तालुका स्तर के कुछ असंतुष्टों का भी निलंबन किया गया.

आक्रमण का दूसरा दौर 2 जुलाई को शुरू हुआ जब पार्टी की गौडा समर्थक हासन और मांड्या जिला समितियां भंग कर दी गईं. उसी दिन हेगड़े ने एक संवाददाता सम्मेलन में देवगौडा पर उनकी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी बताया कि देवगौडा ने तो राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के नाम दो पत्रों का मसौदा भी तैयार कर लिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका गुट सरकार को समर्थन नहीं देगा. हेगड़े ने बताया, "पत्र देने का इरादा पर्याप्त समर्थन न जुटा पाने के कारण छोड़ दिया गया."

हेगड़े समर्थकों का आरोप है कि 1979 में चरण सिंह ने केंद्र में जनता सरकार के साथ जो किया था वही देवगौडा हेगड़े सरकार के साथ करना चाहते थे. लेकिन देवगौडा इस आरोप से साफ बचने की कोशिश करते हुए कहते हैं, "मेरी तरह चरण सिंह को भी किसानों के हितों की चिंता थी." परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद अगले दिन देवगौडा ने आरोप लगाया, "यह महज एक चुनावी हथकंडा था. इसके लिए हेगड़े को एक दिन पछताना पड़ेगा. इससे साबित हो गया है कि वे कितने हताश हैं, संतुलन खो चुके हैं." देवगौडा की दलील थी कि उनके हस्ताक्षर अभियान का मकसद विधायक दल की बैठक में विश्वास मत हासिल करते समय हेगड़े द्वारा पार्टी आलाकमान के आदेश की अवहेलना का विरोध भर करना था. (देखें इंडिया टुडे, 31 मई '88).

मामला सुलटाने का दावा करने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह असंतुष्ट नेता देवगौडा को शह देते रहे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रामकृष्ण हेगड़े

'गौडा की गद्दारी से दुखी हूं'

कर्नाटक जनता पार्टी में असंतोष की आंच ने मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. पीठ में तकलीफ की वजह से वे कई दिनों से बिस्तर पर हैं. कड़े और सपाट बिस्तर पर आराम कर रहे थके-मांदे हेगड़े ने प्रमुख संवाददाता ***अनीता प्रताप*** *से एक घंटा बातचीत की. कुछ अंश:*

मुश्ताक अहमद

• 3 जुलाई के चुनाव परिणामों पर आपकी प्रतिक्रिया?

मैं खुश नहीं हूं क्योंकि हम आसानी से और सीटें जीत सकते थे. पर नतीजों ने साबित कर दिया है कि असंतुष्टों का प्रभाव उन जिलों तक ही सीमित है जहां उनकी जाति (वोक्क?लिगा) का बहुमत है.

• चुनाव की पूर्व संध्या पर अजीत सिंह के इस बयान से कि हमारा कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, आप कुपित दिखते हैं.

बतौर पार्टी अध्यक्ष वे ऐसा बयान कैसे जारी कर सकते हैं? उन्होंने खुलेआम (असंतुष्टों की) तरफदारी की है. इससे असंतुष्टों को प्रोत्साहन ही नहीं मिला, उनकी गतिविधियों को वैधता भी मिली.

• अजीत सिंह के बयान को आप दुर्भाविनापूर्ण मानते हैं या उनकी अपरिपक्वता और अनुभवहीनता का नतीजा?

इन सभी का मिश्रण. बेहद शालीन भाषा में कहूं तो वे कोई बड़े विद्वान नहीं हैं.

• क्या आपकी ओर से अभी और मुअत्तलियों की संभावना है?

हां. कुछ और लोगों को निष्कासित और निलंबित किया जाएगा. अगर देवगौडा इन अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को मान लेते हैं और सहयोग को सहमत हो जाते हैं तो मैं उन्हें एक और मौका देने को तैयार हूं. वरना मुझे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा.

• तो क्या पार्टी टूट जाएगी?

मुझे नहीं पता. अगर ऐसा होता भी है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि गुटबंदी और अनियंत्रित अनुशासनहीनता के साये में पार्टी बनाना संभव नहीं.

• कहा जा रहा है कि आपका गुट जनमोर्चा में शामिल हो जाएगा.

हमें क्यों जाएं? पार्टी में जब हमारा बहुमत है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता.

• क्या अब आपका मोहभंग हो गया है?

हां. सबसे ज्यादा वेदना और मोहभंग तो गौडा की गद्दारी की वजह से हुआ है. मैंने उन्हें पूरी आजादी दे रखी थी ताकि मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम देख सकूं. निजी प्रतिष्ठा पर बट्टा लगने से मेरा मोहभंग है. छह महीने पहले मुझे राजीव गांधी का विकल्प कहा जाता था पर आज अपने ही गृह राज्य में गुट का नेता बताया जाता है.

इसके बाद चुनाव आ गए और हेगड़े ने विरोधी खेमे पर दूसरा आक्रमण किया. प्रदेश पार्टी अध्यक्ष एम.पी. प्रकाश ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह असंतुष्टों को निलंबित कर दिया. ये हैं— नारायणराव, बायरे गौडा, वर्दे गौडा, एन.एस. खेड, एस.डी. जयराम और बी.बी. गुरुप्रसाद. प्रकाश कहते हैं, "मैंने उन्हीं असंतुष्टों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनके खिलाफ जिला इकाइयों ने सबूत पेश किए हैं."

लेकिन असंतुष्ट विधायक यह मानने को तैयार नहीं. बायरे गौडा के अनुसार, "यह कार्रवाई असंवैधानिक और बदले की भावना से प्रेरित है." असंतुष्टों की दलील है कि प्रदेश अध्यक्ष को विधायकों और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार नहीं है. बहरहाल, प्रकाश यह दलील तो दे ही सकते हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं.

27 जून को राजस्वमंत्री एस.आर. बोम्मई के बेटे की शादी के अवसर पर बंगलूर में पार्टी के प्रायः सभी केंद्रीय नेता इकट्ठे हुए थे. तीन दिन तक ये नेता दोनों धड़ों को कम-से-कम इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे कि वे 3 जुलाई के परिषद चुनावों तक तो एक रहें. लेकिन हेगड़े किसी अस्थायी अल्पकालिक समझौते के पक्ष में नहीं थे.

इन वार्ताओं से कुछ हासिल तो नहीं ही हुआ, पार्टी आलाकमान की दुर्बलताएं जरूर उभरकर सामने आईं. पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह के लिए अपनी क्षमता दिखाने का यह पहला मौका था और वे बुरी तरह चूक गए. 27 जून को बंगलूर पहुंचने पर अजीत ने जोर देकर कहा था कि "समझौता तो कराना ही पड़ेगा. इस समस्या का समाधान मेरे पास है." लेकिन उनकी हरकतें इससे उलट ही थीं. गौडा ने यह कहा कि अजीत की मान्यता है कि पार्टी की राज्य शाखा को जिला समितियों को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है. अजीत ने गौडा के इस बयान का खंडन नहीं किया. वे तब भी चुप रहे जब दो जिला समितियों के गौडा समर्थक अध्यक्षों ने परिषद चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया.

लेकिन हेगड़े समर्थकों की ज्यादा नाराजगी अजीत के उस बयान को लेकर थी जो उन्होंने परिषद चुनाव से पहले दिया था. एक इंटरव्यू में अजीत ने कहा था कि चूंकि पार्टी आलाकमान ने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है इसलिए असंतुष्ट गुट के उम्मीदवार भी जनता पार्टी के ही उम्मीदवार हैं. और हेगड़े ने अजीत को एक कड़ी चिट्ठी लिखी कि यदि उन्हें और प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश को 'बाहरी हस्तक्षेप के बिना अंदरूनी झगड़े सुलझाने' की छूट नहीं दी जाती तो उन्हें विधायक दल के नेता के पद से मुक्त किया जाए. हेगड़े ने चिट्ठी में लिखा, "मुझे उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान की यह मंशा नहीं रही होगी कि असंतुष्टों को इतनी छूट दे दी जाए कि वे मुझे कर्नाटक की अंदरूनी समस्याओं में ही उलझाए रखें."

हेगड़े की आशंकाएं निराधार नहीं थीं. 10 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से देवगौडा और अजीत की एक टेलीफोन वार्ता का टेपांकित ब्यौरा छपा. 1 जुलाई को हुई इस वार्ता में देवगौडा ने जब अजीत को बताया कि बागी उम्मीदवार जीतने वाले हैं तो अजीत जैसे गद्गद् हो गए और उन्होंने जवाब दिया, "बहुत खूब! आप जीत गए तो बस ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे."

इस वार्ता से साफ है कि अजीत देवगौडा की हौसलाअफजाई करते रहे हैं. उन्होंने असंतुष्ट नेता को आश्वासन दिया कि वे जिला समितियों के विघटन पर रोक लगवाने की कोशिश करेंगे. अजीत ने देवगौडा को यह भी सिखाया कि वे यह बयान दें कि संसदीय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

ले डूबे सनम

कर्नाटक में इंका यही आस लगाए दिखती है कि कब उसकी किस्मत पलटे. 3 जुलाई को स्थानीय निकाय क्षेत्रों से विधान परिषद के चुनाव नतीजों से यही जाहिर होता है कि जनता पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से इंका ही फायदे में रही. बहरहाल, राज्य में चुनाव का यह तीसरा और अंतिम दौर बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जिला परिषदों और मंडल पंचायतों के 58,399 सदस्यों की भागीदारी रही.

जनता पार्टी के वोट बंट जाने से इंका ने तुमकूर, कोलार, बीदर, चित्रदुर्ग और बेलगाय की पांच अतिरिक्त सीटें बटोर लीं. कुल 24 सीटों में से जनता पार्टी को 13, इंका को 9 और पूर्व मंत्री एच.डी. देवगौडा समर्थित जनता विद्रोहियो को 2 सीटें मिलीं. महत्वपूर्ण तो यह है कि जहां जनता पार्टी को कुल पड़े वोटों का 44.27 फीसदी मिला, वहीं इंका 41.05 फीसदी वोट बटोर ले गई और जनता पार्टी के असंतुष्टों को 9.84 फीसदी मत मिले. यानी 3 जुलाई के चुनावों ने साबित कर दिया है कि जनता पार्टी की फूट इंका को फायदे में रखेगी.

मगर जनता पार्टी चुनाव नतीजों से अविचलित रही. जनता नेता मधु दंडवते ने इसे 'ग्रामीण जनता में हेगड़े की लोकप्रियता का सबूत' बताया. गौर से देखें तो यही लगता है कि लोगों में हेगड़े ही लोकप्रिय हैं, देवगौडा नहीं. नतीजों ने असंतुष्ट खेमे की हवा भी सरका दी है. इनसे यही साबित हुआ कि विद्रोहियों का प्रभाव सिर्फ वोक्कालिगा बहुल इलाकों तक ही सीमित है. दिल खोलकर खर्च किए जाने के बावजूद उन्हें दो सीटें ही हाथ लगीं—एक गौडा के गृह जिला हासन की और दूसरी मांड्या की.

वोक्कालिगा बहुल मैसूर में गौडा के अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और ग्रामीण बंगलूर जिलों में भी गौडा गुट के उम्मीदवार के तीसरे स्थान पर रहने के कारण उसे करारी हार का मुंह देखना पड़ा. फिर भी असंतुष्टों का दावा है कि 12 अधिकृत उम्मीदवारों में से चार उनके समर्थन से ही जीत सके. पर हेगड़े समर्थकों का कहना है कि इन चार सीटों पर असंतुष्टों की सक्रियता के बावजूद उन्हें कामयाबी मिली है. यह बात पूरी तरह से सही न हो पर गुलबर्गा और चित्रदुर्ग में निश्चय ही जनता पार्टी के खाते में क्रमशः 235 और 391 वोटों की गिरावट आई है.

उधर तुमकूर में जनता पार्टी के वोट बंटने से इंका की जीत सहज हो गई. यहां इंका को 1705, जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को 1593 और विद्रोही गुट को 768 वोट मिले. इन चुनावों में जीत सामान्य बहुमत के आधार पर न आंकी जाकर चूंकि वरीयता वोट के आधार पर होती है, इसलिए विद्रोही उम्मीदवार को मिले मत द्वितीय वरीयता में अगर जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को मिलते तो वह जीत सकता था.

इस चुनाव से एक तथ्य यह उभरता है कि असंतुष्ट खेमे में विसंगतियां तो हैं ही, उसमें प्रतिबद्धता का भी अभाव है. कुछ हलकों में तो विद्रोहियों ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में ही काम किया. लेकिन हेगड़े के प्रति उनमें घृणा भाव इतना जबरदस्त है कि कुछ हलकों में उन्होंने अपने पार्टी उम्मीदवार के बजाय इंका को वोट देना पसंद किया.

राज्य की सत्ताधारी जनता पार्टी में असंतोष का घुन लगने से इंका भविष्य के प्रति आशावान हो सकती है.

—अनीता प्रताप

बोर्ड ने अधिकृत उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की है. इसलिए असंतुष्टों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती.

बहरहाल, अब प्रश्न यह है कि हेगड़े की आक्रामकता और अजीत के इरादों के भंडाफोड़ के कारण क्या पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है. हेगड़े के एक समर्थक का कहना है, "लगता है पार्टी को तोड़ने के मामले में अजीत अपने पिता के पदचिन्हों पर चल पड़े हैं." उधर हेगड़े अपनी मुहिम आगे बढाने पर दृढ़ दिखते हैं.

पर्यवेक्षकों का कहना है कि तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो नुकसान एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी पार्टी को होगा. पूर्व पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर और अजीत सिंह जिस तरह हेगड़े के सामने अड़चनें खड़ी कर रहे हैं

मुश्ताक अहमद

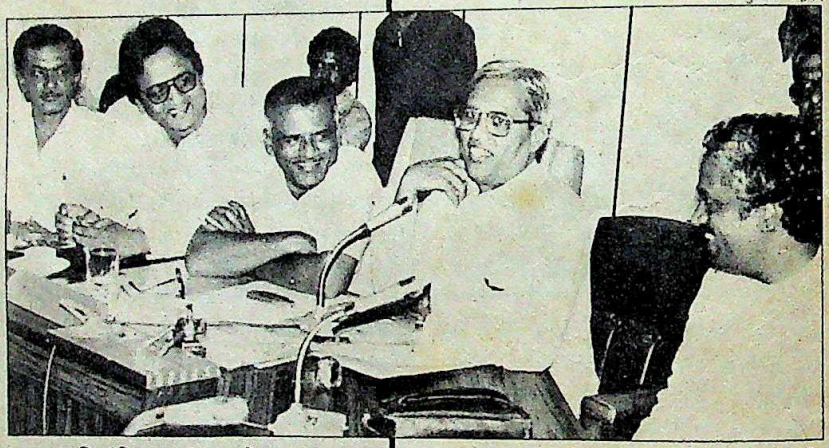

निलंबित असुंतष्ट नेता

उस कारण भी हेगड़े जनमोर्चा नेता वी.पी. सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल द्वारा प्रस्तावित विपक्षी मोर्चे की ओर खिंचते जा रहे हैं. पार्टी में फूट राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है. तब हेगड़े, मधु दंडवते, बीजू पटनायक और जॉर्ज फर्नांडीस जैसे नेता नए विपक्षी मोर्चे में जा सकते हैं.

लेकिन यह दो बातों पर निर्भर है. एक तो यह कि वी.पी. सिंह अपने साथ किन पार्टियों या लोगों को मिलाना चाहते हैं और दूसरे, इंका में विभाजन की क्या संभावनाएं हैं. लेकिन वी.पी. सिंह ने जान-बूझ कर या असमंजस के कारण अपनी भावी रणनीति के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है. और कांग्रेसी भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगामी चुनाव में दांव किस पर लगाएं—राजीव की इंका पर या वी.पी. सिंह वाले संभावित मोर्चे पर. इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जब तक कोई निश्चित ध्रुवीकरण नहीं हो जाता, हेगड़े को अपने तीखे तेवर के साथ बागियों से जूझते ही रहना होगा.

—अनीता प्रताप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जानकार लोगों की चाहत

ऐस्प्रो राहत

सरदर्द का बेहतरीन उपचार

दुनिया भर के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय दवा

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपनी उखड़ी जड़ों को फिर से जमाने की रणनीति के तहत इंका आलाकमान ने वहां के नेतृत्व में पिछले दिनों परिवर्तन कर दिए. उसे भरोसा है कि इस परिवर्तन से पार्टी की स्थिति मजबूत होगी. लोकसभा में इन दोनों राज्यों से कुल मिलाकर 133 सीटें हैं. दिसंबर 1984 में हुए आम चुनाव में इंका को इन दोनों राज्यों से कुल 123 सीटें मिली थीं.

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अगले आम चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये परिवर्तन किए हैं. दोनों राज्यों के कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व अब ऐसे महारथियों के हाथों में सौंपा गया है जो हर मुश्किल से जूझने में माहिर माने जाते हैं.

नए मुख्यमंत्रियों—नारायणदत्त तिवारी और शरद पवार—के लिए शुरू के कुछ हफ्ते उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के मद्देनजर अहम होंगे. दोनों को न सिर्फ अपने-अपने राज्य में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर काबू पाना होगा बल्कि शक्तिशाली विपक्ष को भी बेअसर करना होगा. इंका को उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनमोर्चा से और महाराष्ट्र में शिवसेना से गंभीर खतरा पैदा हो गया है. जाहिर है, इन दोनों नेताओं को अपने राजनैतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है. प्रस्तुत है उनकी रणनीतियों और उनके सामने आने वाली समस्याओं का विवेचनः

उत्तर प्रदेश

कठिन राह राजनीति की

विरासत में मिली मुश्किलों से जूझने को तिवारी तैयार

मैं नए मुख्यमंत्री के लिए समस्यामुक्त राज्य छोड़े जा रहा हूं.
—बीरबहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद

इस बयान से आज अगर कोई पूरी तरह असहमत होगा तो वह हैं बीरबहादुर सिंह के उत्तराधिकारी नारायणदत्त तिवारी. अगले आम चुनाव की दृष्टि से एकमात्र अति महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी पर पिछले पखवाड़े अनमने ढंग से बैठने वाले तिवारी सत्ता सूत्र संभालते ही जान गए कि नया काम कितना मुश्किलों भरा है. उन्हें उत्तराधिकार में खाली राजकोष, अनुशासनहीन नौकरशाही, मृतप्राय पार्टी संगठन, लाड़-प्यार से बिगड़े हुए विधायक और इन सबसे ज्यादा विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में नींद हराम करने वाला एक शक्तिशाली राजनैतिक दुश्मन मिला है. जैसा कि तिवारी ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत में माना, "उत्तर प्रदेश में कामकाज करने के तरीके में बेहद सुधार की जरूरत है."

कामकाज के तरीके में सुधार की कितनी जरूरत है, यह राज्य प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ हुई उनकी पहली बैठक से ही साफ हो गया. यह बैठक 12 घंटे तक चली. यह अपने आप में एक रिकार्ड है. तिवारी यह देखकर स्तब्ध रह गए कि ज्यादातर अधिकारी लटकी पड़ी परियोजनाओं या फैसलों के बारे में ठीक-ठीक ब्यौरा नहीं दे सके. एक वरिष्ठ सचिव ने कहा, "तीन वर्षों से यहां एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो राज्य प्रशासन की बनिस्बत राजनीति

उत्तर प्रदेश के इंकाइयों के साथ तिवारीः बिखरे हुओं को जोड़ने की चुनौती

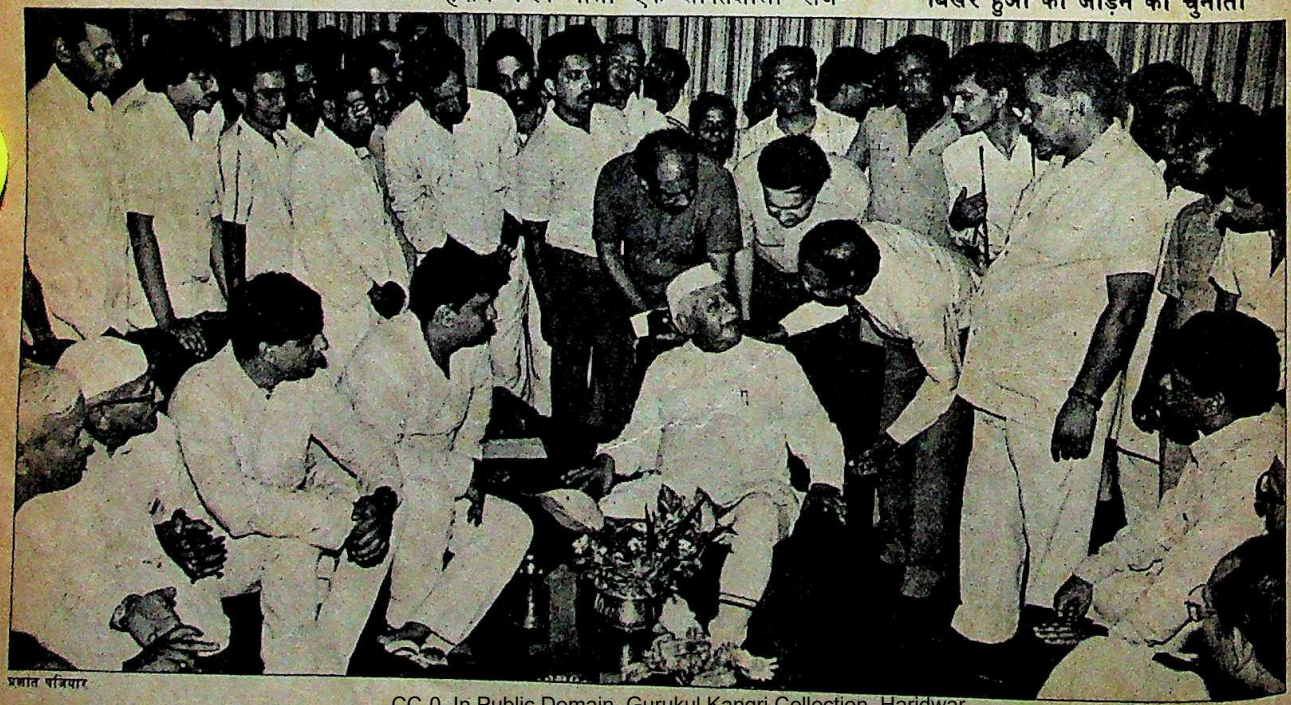

प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में ज्यादा दिलचस्पी रखता था. लिहाजा हममें से ज्यादातर ने कामकाज अपने सहायकों के जिम्मे छोड़ दिया था."

लेकिन दूसरे अफसरों का कहना है कि बीरबहादुर सिंह के राज में नौकरशाहों की उदासीनता का मुख्य कारण था प्रशासन के ऊपरी ढांचे में हुआ तीव्र जातिगत विभाजन. इस विभाजन ने अतिरिक्त प्रशासनिक परेशानियां पैदा कीं. चूंकि बीरबहादुर ठाकुर हैं, इसलिए उन्होंने हरिजन अफसरों को लोक निर्माण, आबकारी, शहरी विकास और बिजली जैसे विभाग देकर हरिजन लॉबी को खुश करने की कोशिश की.

इससे भी ज्यादा अहम बात यह कि उनके राज में मुख्यमंत्री का दफ्तर अफसरों से भर गया था. उनके दफ्तर में तीन सचिव, दो विशेष सचिव, तीन संयुक्त सचिव, तीन उप सचिव, तीन सलाहकार और एक दर्जन मध्यम दर्जे के अधिकारी थे. चूंकि समूचा प्रशासन मुख्यमंत्री के दफ्तर से चलाया जा रहा था, लिहाजा ज्यादातर अधिकारियों ने अपने काम में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया. लेकिन जैसा कि तिवारी खुद मानते हैं, सबसे ज्यादा गिरावट कामकाज के स्तर में आई है. मिसाल के तौर पर पिछले छह महीने के दौरान राज्य के लगभग सभी मंत्रियों ने दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताया.

लेकिन तिवारी को यकीन है कि वे प्रशासन को ज्यादा जिम्मेदार बनाएंगे. उन्होंने एक बड़ा नीतिगत फैसला किया है. उन्होंने आदेश दिया है कि किसी भी अफसर को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान अपने विभाग के बारे में कुछ बताने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके बदले कैबिनेट मंत्री को खुद ही मंत्रिमंडल के सामने अपना मामला रखना होगा. उन्होंने इसकी एक मिसाल भी पेश की. उन्होंने व्यक्तिगत कार्रवाई के लिए उन सभी लंबित केंद्रीय परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लिया है जिन्हें अभी नई दिल्ली से मंजूरी नहीं मिली है. पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार के हाथ से दो बड़ी औद्योगिक इकाइयां निकल गईं. एक तो स्वराज पॉल द्वारा बैठायां जाने वाला एक उर्वरक संयंत्र था और दूसरा एक ऐरोमैटिक संयंत्र. स्वराज पॉल राज्य सरकार के असहयोग के कारण पीछे हट गए जबकि ऐरोमैटिक संयंत्र का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार परियोजना के लिए किसी सहयोगी कंपनी के बारे में फैसला नहीं कर सकी.

तिवारी का कहना है कि वे ग्रामीण विकास, सड़कों का जाल बिछाने और 20 सूत्री कार्यक्रम पर तेजी से अमल करने पर जोर देंगे. केंद्रीय वित्तमंत्री रहने और पार्टी

नारायणदत्त तिवारी

'मुख्यमंत्री पद का इच्छुक न था'

*उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद नारायणदत्त तिवारी का जाना पहचाना है. पिछली दो बार की तरह अब उन्हें फिर पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए लखनऊ भेजा गया है. नई जिम्मेदारी संभालने पर तिवारी से हाल ही में वरिष्ठ संपादक **प्रभु चावला** ने बातचीत की. कुछ अंश:*

● ***आप उत्तर प्रदेश लौटने के इच्छुक***

रेखाचित्र: पियली दत्त गुप्त

नहीं थे. फिर आप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे?

हां, पहले मैं इस पद का इच्छुक नहीं था पर अब मैंने नई जिम्मेदारी से तालमेल बिठा लिया है.

● ***क्या यह सही है कि आपको राजीव गांधी का विकल्प माने जाने के कारण केंद्र से हटा दिया गया?***

जो लोग मुझे राजीव गांधी का विकल्प मानते हैं, मैं उनका आभारी हूं. हो सकता है मेरे कुछ खैरख्वाहों ने ऐसा सोचा हो. मगर मुझे यह ख्याल कभी नहीं सूझा. यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी मुझे इसीलिए बुजदिल करार दे चुके हैं क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री पद की उनकी पेशकश ठुकरा दी थी.

● ***मौजूदा पद स्वीकार करने से पहले क्या आपने कोई शर्त रखी थी?***

मैंने प्रधानमंत्री से सिर्फ यह अनुरोध किया कि राज्य सरकार को केंद्र का पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए.

● ***क्या आप महज विकास पर ज्यादा पैसा खर्चकर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे? पार्टी नेताओं की बिगड़ी छवि को आप कैसे सुधार पाएंगे?***

राष्ट्रीय मुद्दों की भूमिका अहम तो है. पर हम ठीक काम करके लोगों में भरोसा जगा सकते हैं. अगर हम सिद्ध कर सकें कि कांग्रेस ही टिकाऊ सरकार दे सकती है तो लोग बेबुनियाद आरोपों की अनदेखी कर देंगे.

"जो लोग मुझे राजीव गांधी का विकल्प मानते हैं मैं उनका आभारी हूं. हो सकता है मेरे कुछ खैरख्वाहों ने ऐसा सोचा हो. मगर मुझे यह ख्याल कभी नहीं सूझा"

● ***लेकिन आप मंत्रियों की उसी टोली और वैसे ही निष्क्रिय पार्टी संगठन से कैसे काम चला सकते हैं?***

जैसे लोग उपलब्ध हैं हमें उन्हीं से काम चलाना होगा. और फिर सभी कैबिनेट मंत्री अनुभवी और योग्य हैं. मैंने उनमें बहुतों के विभाग बदल दिए हैं ताकि हर विभाग को नया नेतृत्व मिल सके.

● ***मगर अल्पसंख्यकों और हरिजनों के पार्टी में भरोसा खो दिया लगता है.***

हां, उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है. उनका ख्याल गलत है कि मेरठ के दंगों और राम जन्मभूमि विवाद को ठीक ढंग से नहीं निबटाया जा रहा. मैं यह भावना मिटाऊंगा.

● ***वी.पी. सिंह और जनमोर्चे की ओर से खतरे के प्रति आप क्या करेंगे?***

फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता. वक्त आने पर हम इससे भी निबट लेंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आलाकमान का पूरा समर्थन हासिल होने के कारण, केंद्र से धन पाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.

लेकिन तिवारी की सबसे बड़ी समस्या है 300 इंका विधायक और विधान परिषद के सदस्य. ये सभी बीरबहादुर सिंह के कार्यकाल में ज्यादा तवज्जो देने से 'बिगड़' गए हैं. देश में सबसे अधिक पैसा पाने वाले इन विधायकों को नौकरशाहों के तबादले और तरक्की के मामलों में अभूतपूर्व अधिकार मिले हुए हैं. तिवारी ने पाया कि कुछ मंत्रियों ने तीन साल में 300 तबादलों के आदेश दिए जिससे राज्य के 59 में से 20 जिलों का प्रशासन प्रभावित हुआ.

मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के तुरंत बाद तिवारी ने तबादलों के आदेश रद्द करके स्पष्ट कर दिया कि विधायकों का राज अब खत्म हो गया है. दरअसल तिवारी ने अपना मंत्रिमंडल अभी पूरा नहीं भरा है. वे कोई फैसला लेने से पहले पिछले मंत्रियों के कामकाज का जायजा ले रहे हैं.

इन सबसे संकेत मिलता है कि तिवारी राज्य प्रशासन को व्यवस्थित करने में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं. लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं है. आम चुनाव बमुश्किल 18 महीने दूर हैं. उनकी पहली परीक्षा कुछ हफ्ते बाद चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव में होगी. इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के कई बड़े राजनैतिक नेता अब विपक्षी खेमे में हैं. इंका के पास बहुत ही कम प्रभावशाली नेता हैं. इसके अतिरिक्त लोकपति त्रिपाठी जैसे कई प्रमुख नेता तिवारी की नियुक्ति से नाखुश हैं. त्रिपाठी को उम्मीद थी कि बीरबहादुर सिंह की जगह उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. तिवारी के सामने मुसलमानों को पटाने की भी कड़ी चुनौती है. बीरबहादुर सिंह जो हिंदूवादी छवि बनाकर छोड़ गए हैं, उससे मुसलमान भी इंका से खफा हैं.

कुल मिलाकर तिवारी के सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया है. अपने मन की करने वाले मंत्रियों और विधायकों पर अंकुश लगाकर वे असंतोष को ही बढ़ावा देंगे. दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए पहले ही खतरा बन चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके जनमोर्चा का असर बढ़ता जा रहा है और उनकी संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं. नौकरशाही को चुस्त-दुरुस्त बनाने की तिवारी की कोशिशों का भी निश्चित रूप से कड़ा विरोध होगा. लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तिवारी का चौथा कार्यकाल उनके लिए अब तक की सबसे कड़ी चुनौती साबित होगा.

—प्रमु चावला

महाराष्ट्र

शरद का सामना ग्रीष्म से

पार्टी को एकजुट करने के अलावा विपक्ष से जूझना भी है

सबसे बड़ी तब्दीली तो कार्यशैली की दिखती है. जहां शंकरराव चव्हाण संकोची और अल्पभाषी थे, वहीं उनकी जगह कुर्सी पर विराजमान हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार हर रोज बंबई में सत्ता के गलियारों में जुटते सैकड़ों खादीधारी इंकाइयों के बीच घिरे रहना पसंद करते हैं. वे रोजाना करीब 2,000 लोगों से मिलते हैं. करीब 18 घंटे दैनिक काम की उनकी कार्यसूची में मुलाकातियों के लिए समय के अलावा विधानसभा सत्र में मौजूद रहना और अपने दफ्तर में आने वाली फाइलों को निबटाना शामिल है. आठ साल से ज्यादा अरसे बाद सत्ता में लौटे पंवार इन दिनों हर क्षण का भरपूर लुत्फ उठा रहे दिखते हैं.

लेकिन उनकी यह महत्वाकांक्षा आसानी से पूरी नहीं हुई. कई साल तक विपक्ष में रहने के बाद पवार दिसंबर 1986 में इंका में इस आस से लौटे कि छह महीने के अंदर उन्हें राज्य की बागडोर सौंप दी जाएगी. पर उन्हें 18 महीने इंतजार भोगना पड़ा. इस बीच वे राज्य में शिवसेना के शेर को जवान होते और खुद अपने समर्थकों का हौसला पस्त होते देखते रहे. आखिर जब पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी से बुलावा आया तो पवार के सामने स्थिति एकदम स्पष्ट थी.

बंबई के राजभवन में शपथ समारोह के लिए जल्दबाजी में बुलाए गए नेताओं से भी दो बातों का अंदाज लगा. एक यह कि पवार को कुर्सी केंद्र की मेहरबानी से मिली है और दूसरे यह कि राज्य में पार्टी के दिग्गज और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल वसंतदादा पाटील की दबी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने की जरूरत है. मंच पर राज्यपाल ब्रह्मानंद रेड्डी की बगल में केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह और माखनलाल फोतेदार बैठे थे, जिन्हें आलाकमान ने महाराष्ट्र में निर्विघ्न फेरबदल के लिए भेजा था. पहले दिन शपथ लेने वाले छह काबीना मंत्रियों में पांच तो आलाकमान द्वारा नामजद हैं या पाटील के समर्थक माने जाते हैं जबकि छठे पद्म सिंह पाटील नए मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र के इंका नेताओं को संबोधित करते पवार: एकता पर जोर

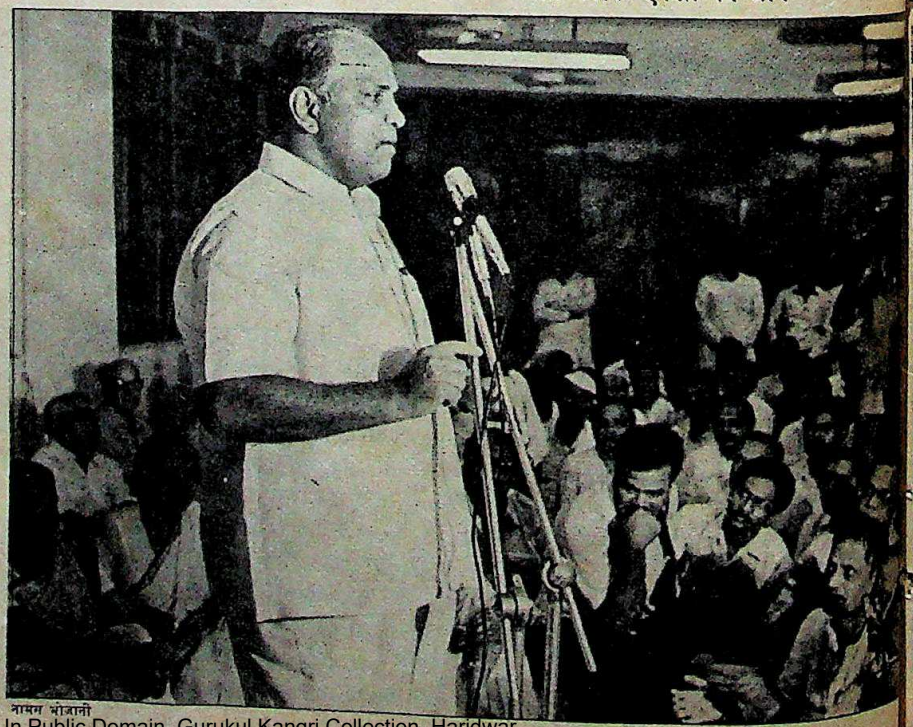

नामन भोजानी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के रिश्तेदार हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं.

यहां तक कि दो दिन बाद शपथ लेने वालों समेत 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल में आठ ही मंत्री ऐसे हैं जो 1986 में पवार के साथ इंका में शामिल हुए थे. बाकी या तो पाटील समर्थक हैं या फिर दिल्ली में बैठे किसी न किसी नेता के वफादार. मंत्रिमंडल में बहुमत निश्चित रूप से मराठा जाति का है पर उसमें अनुसूचित जातियों-जनजातियों, मुसलमानों, मारवाड़ियों और पिछड़ी जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिला है. आंबेडकर के अनुयायी नवबौद्धों को ही इसमें जगह नहीं दी गई है. कई वर्षों के बाद एक ब्राह्मण और एक पारसी को भी मंत्रिमंडल में लिया गया है.

खुद पवार ने मंत्रिमंडल के गठन के बारे में सवालों के सधे हुए जवाब दिए. उनका कहना है कि उनको मंत्री चुनने की खुली छूट दी गई और वे सभी कांग्रेसी हैं, इस या उस नेता के समर्थक नहीं. लेकिन रामराव आदिक और जवाहरलाल दर्डा सरीखे विवादास्पद नेताओं को शामिल करने पर 'महाराष्ट्र टाइम्स' के संपादक गोविंद तलवलकर जैसे पवार के पुराने समर्थकों ने भी उनकी आलोचना की.

आदिक और दर्डा दोनों अभी से संकेत देने लगे हैं कि उनके नाम अक्सर सुर्खियों में रहेंगे. लोक स्वास्थ्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही दर्डा का नाम अंतरराज्यीय शराब घोटाले के कारण चर्चित हो उठा. यह घोटाला उस समय का है जब वे वसंतदादा पाटील सरकार में मद्यनिषेधमंत्री थे. उद्योगमंत्री आदिक ने

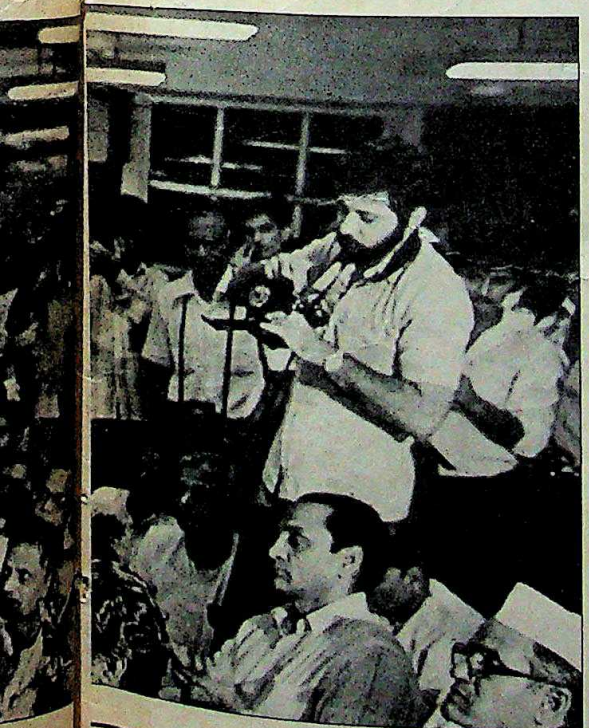

शरद पवार

'बदलाव तो होना ही था'

शरद पवार के मुख्यमंत्री बनते ही महाराष्ट्र के सभी भागों से पार्टी कार्यकर्ता बंबई की ओर उमड़ पड़े. पर 48 वर्षीय तेजतर्रार पवार ने गृह जिले पुणे से आए एक शिष्टमंडल से मुलाकात के बाद आधी रात को राज्य के अतिथि गृह में ब्यूरो प्रमुख ***एम. रहमान*** *से बातचीत की.*

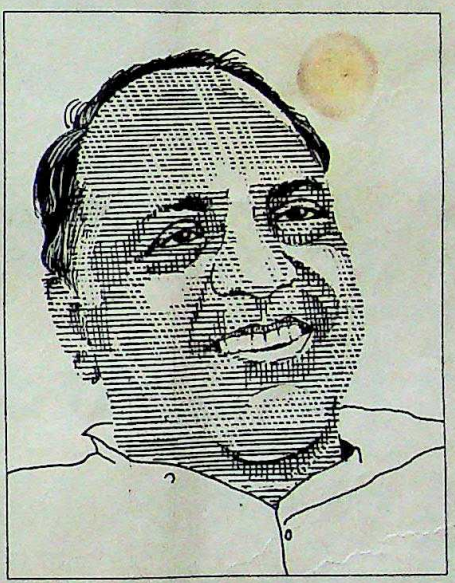

● *हाल के उपचुनावों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए क्या आपको अगले आम चुनाव में राज्य से इंका की जीत पक्की करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है?*

जो कोई राज्य चलाने की जिम्मेदारी लेगा उसे चुनाव में पार्टी की जीत पक्की करने का दायित्व तो उठाना ही होगा. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन अप्रत्याशित नहीं हैं. इस पर एक साल से विचार चल रहा था.

● *क्या ऐसा नहीं लगता कि इंका तेजी से लोकप्रियता खो रही है?*

मैं इन नतीजों को किसी रुझान का संकेत मानने को तैयार नहीं. उपचुनाव अमूमन सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जाते हैं. अब हमें लोगों और पार्टी के हित में सामूहिक तौर पर काम करना है.

● *पार्टी को चुनावों के लिए तैयार करने का आपके पास पर्याप्त समय है?*

नहीं. इसीलिए मैं हर मिनट का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं कांग्रेसजनों का मनोबल बढ़ाना चाहता हूं.

● *पार्टी में पुरानी गुटबंदी क्या रातोरात खत्म हो जाएगी?*

ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है.

● *क्या राज्य में मुख्य चुनौती शिवसेना की ओर से है?*

जिन पार्टियों से मुकाबला करना है शिवसेना भी उनमें एक है. इसके लिए कांग्रेस और युवक कांग्रेस को

"जो राज्य चलाने की जिम्मेदारी लेगा उसे चुनाव में पार्टी की जीत पक्की करने का दायित्व उठाना ही होगा... हमें लोगों और पार्टी के हित में सामूहिक तौर पर काम करना है"

मजबूत बनाने पर जोर दूंगा.

● *शरद जोशी और दत्ता सामंत के साथ वी.पी. सिंह के गठजोड़ के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा?*

वी.पी. सिंह की कोई लहर चल पड़ेगी, यह कहना सही नहीं. मैं नहीं समझता वे राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती बन सकेंगे. कांग्रेस अगला चुनाव जीतेगी ही.

● *पर अगर विपक्ष एक नेता के तहत इकट्ठा हो गया तो?*

यह सब परिकल्पना है. जिस तरीके से वे अब चल रहे हैं उससे संकेत मिलता है कि उनका क्या हश्र होगा.

● *क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका निभा पाएंगे?*

मैं तो महाराष्ट्र पर ही ध्यान दे रहा हूं. मेरा काम यहां पार्टी बनाना और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना है.

● *और आम चुनावों के बाद?*

मैं नहीं जानता तब क्या होगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विधानसभा में यह घोषणा करके सबको चौंका दिया कि नई सरकार पूर्व मंत्रिमंडल के शून्य आधारित बजट के प्रस्ताव पर दुबारा विचार करने को तैयार है. सरकारी कर्मचारी इस प्रस्ताव का जमकर विरोध करते आए हैं क्योंकि इससे सरकारी नौकरियों में ताजा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग जाता है. लेकिन राज्य के बजट में से 2,800 करोड़ रु. 12 लाख सरकारी कर्मचारियों के मद में चले जाते हैं जबकि बजट की नई प्रणाली पर अमल के पहले साल ही 50 करोड़ रु. की बचत हुई है.

दरअसल विधायकों को हैरत इस बात पर हुई कि बजट पर बयान वित्तमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने न देकर आदिक ने दिया. सवाल यह उठाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में अत्यधिक महत्वाकांक्षी नेताओं को शामिल करके क्या पवार एक विभाजित टीम के मुखिया बने हैं.

लेकिन नए मंत्रिमंडल के गठन से पवार पर न सिर्फ बाहरी दबावों की ही बात उजागर होती है बल्कि उनका यह एहसास भी झलकता है कि अगले आम चुनाव में इंका को जिताने के लिए उन्हें सत्ताधारी दल के सभी गुटों को साथ लेकर चलना होगा. जाहिर है पवार को इस आशंका के चलते सत्ता सौंपी गई है कि अगले चुनाव में इंका को शायद मात खानी पड़े. राज्य में वही एकमात्र नेता हैं जो इस हालत को बदल सकते हैं. युवा और मराठा होने के अलावा वे अच्छे प्रशासक और अथक प्रचारक के रूप में भी विख्यात हैं. उन्हें राज्य और पार्टी की हालत की अच्छी समझ भी है. उनमें न सिर्फ पार्टी के विभिन्न धड़ों को एकजुट रखने बल्कि विपक्ष, खासकर शिवसेना और शरद जोशी के शेतकरी संघटना की बढ़ती चुनौती का सामना करने की भरपूर क्षमता भी है.

असल में, पवार को अपने राजनैतिक जीवन की सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना है. इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि आने वाले महीनों में नए मुख्यमंत्री प्रशासन और पार्टी को अगले आम चुनाव के लिए तैयार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे. उनकी सरकार से कई लोकप्रिय कार्यक्रमों की उम्मीद की जा रही है, वहीं राज्य इंका अध्यक्ष प्रभाराव को राजस्वमंत्री बनाए जाने के बाद उनके स्थान पर भी किसी सही व्यक्ति की तलाश है. विधानसभा के मानसून सत्र के बाद लगता है पवार महाराष्ट्र में खुद अपने और अपनी पार्टी को सर्वोच्च राजनैतिक हस्ती बनाने के लिए जिलों का दौरा करेंगे. वैसे दौरे करना उन्हें बहुत अधिक भाता भी है. —एम.रहमान

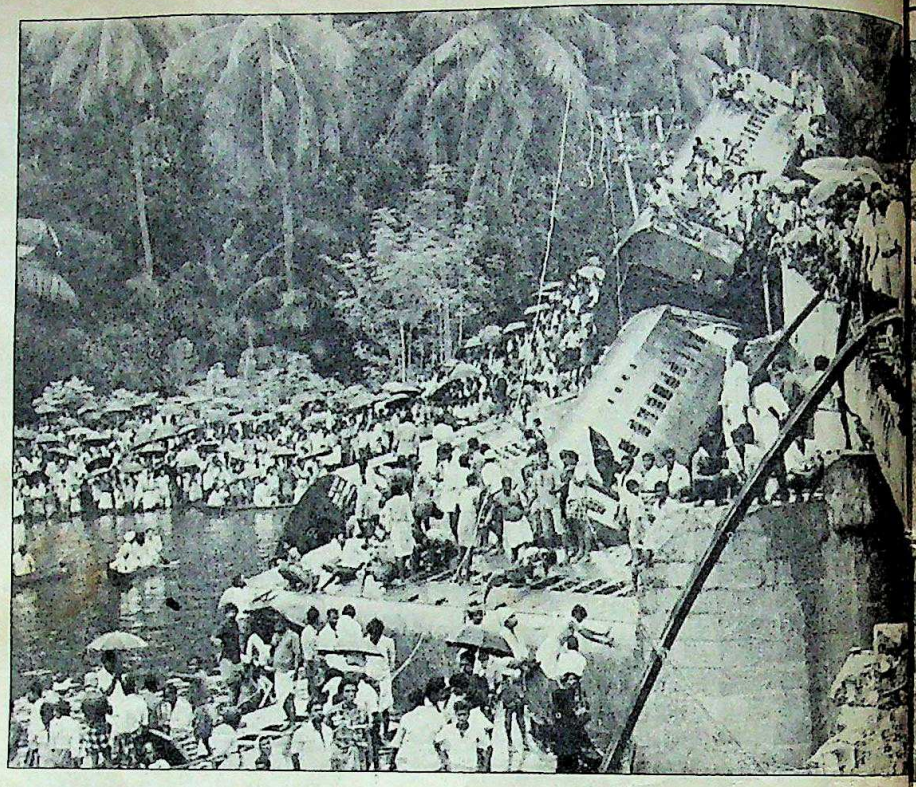

रेल दुर्घटना

दिल दहला देने वाला हादसा

सैकड़ों की जान लेने वाली दुर्घटना के कारण अभी तक अस्पष्ट

दरअसल 8 जुलाई का दिन मर्सी कुट्टी के लिए खुशियां मनाने का दिन था. केरल के कुंदरा चुनावक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इस सांवली, मार्क्सवादी युवती ने अपने पार्टी सहयोगी मुरलीधरन कुरुप के साथ क्विलोन में दोपहर में अपने विवाह की रस्म अभी पूरी ही की थी कि अपने निकटवर्ती चुनावक्षेत्र से उन्हें एक जरूरी बुलावा आ गया. इस दिन की खुशियों से जुड़े अपने कार्यक्रम को एक किनारे रख वे थोड़ी देर बाद ही खूबसूरत झील अष्टमुडी-कायल के पुल पर हुई रेल दुर्घटना से जुड़े राहत कार्य में शामिल हो चुकी थीं. पुल पर हुई रेल दुर्घटना में सौ से ज्यादा यात्री मारे गए थे और इससे भी अधिक घायल हुए थे.

बंगलूर से तिरुअनंतपुरम जाने वाली यह 26-डाउन गाड़ी 'आइलैंड एक्सप्रेस' नाम से भी मशहूर है और भारतीय रेल की धीमी गति वाली गाड़ियों में गिनी जाती है. 8 जून की दोपहर यह गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही थी. ठीक 1 बजकर 12 मिनट हुए थे जब गाड़ी ने क्विलोन से 15 किलोमीटर दूर अष्टमुडी झील के सवा सौ मीटर लंबे खुले पुल में प्रवेश किया और यात्रियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा. गाड़ी के 9 डिब्बे 30 मीटर गहरे पानी में जा गिरे. दुर्घटना के दो दिन बाद तक राहत अभियान में 101 शव बाहर निकाले जा चुके थे.

अपनी तरह की इस सबसे गंभीर दुर्घटना से पूरे केरल राज्य में शोक छा गया जिसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अगले दिन बिना किसी राजनैतिक दल के आह्वान के पूरे राज्य में बंद रहा.

जिस समय गाड़ी पटरी से उतरी उस समय तक उसके 14 डिब्बों में से केवल पार्सल वैन और दूसरे दर्जे का एक डिब्बा तथा इंजन ही पुल पार कर पाए थे. नौ डिब्बे पानी में गिर चुके थे. प्रथम श्रेणी का एक डिब्बा पुल से नीचे लटक रहा था और उसका निचला हिस्सा पानी में डूबा था. दुर्घटना में ज्यादा लोगों के मरने का एक कारण यह रहा कि पानी में गिरते ही दो डिब्बे उलटे हो गए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मधु मगाड

हरीश

■ अष्टमुडी कायल झील में गिरी आइलैंड एक्सप्रेस और राहत में लगी नौकाएं (बाएं)

■ बरामद हुए एक शव को शवगृह ले जाते दमकल कर्मचारी

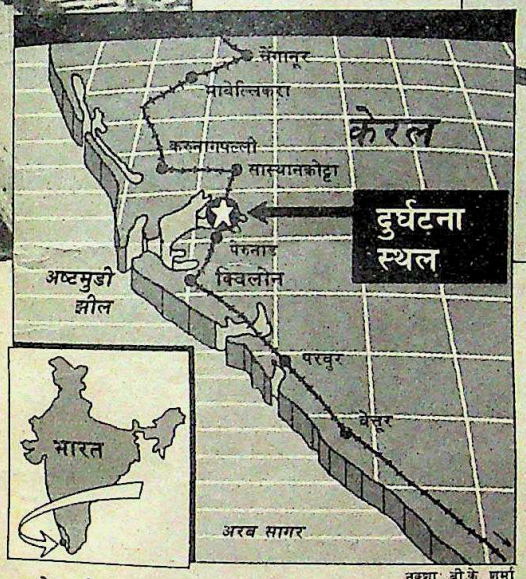

नक्शा: बी.के. शर्मा

इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि बरसात के कारण यात्रियों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली थी.

लेकिन यह भी सच है कि यदि पुल के दोनों ओर बसे गांवों पेरुमान (आबादी: 17 हजार) और मुनरोतुरुतु (आबादी: 9 हजार) से समय पर सहायता न पहुंची होती तो मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा होती. दुर्घटना के तुरंत बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही इसका अनुमान मुनरोतुरुतु में बिजली का काम करने वाले सुरेश कुमार के उदाहरण से लगाया जा सकता है. वह खाना खाकर सो रहा था कि शोर से हड़बड़ाकर उठ बैठा. बाहर आते ही उसने रेलगाड़ी को जब पानी में गिरते हुए देखा तो वह यात्रियों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा.

लोगों ने वहां खड़ी मछलीमार नौकाओं की मदद से सहायता कार्य शुरू कर दिया. केवल दस मिनट के भीतर ही 50 नौकाएं इस अभियान में जुट चुकी थीं. अंदर फंसे यात्रियों को निकालने के लिए लोहे की छड़ों, कुल्हाड़ियों और इस्तेमाल हो सकने वाले हर उपलब्ध हथियार का इस्तेमाल किया गया.

घायल लोगों को क्विलोन जिला अस्पताल और आसपास के प्राइवेट डॉक्टरों तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध सभी वाहनों का इस्तेमाल किया गया. कुछ ही देर में घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और फायर बिग्रेड वाले भी पहुंच गए. क्विलोन के युवा सब-कलेक्टर राजीव सदानंदन का कहना था, "हालांकि हम लोग आधे घंटे के भीतर ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे पर तब तक लोगों ने शानदार तरीके से राहत शुरू कर दिया था."

दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए 140 किलोमीटर दूर कोचिन से नौसेना के 100 गोताखोर और तीन हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में लगा दिए गए. राहत कार्य का मुआयना करने के लिए रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया भी रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ एक विशेष चार्टर विमान से वहां जा पहुंचे. सिंधिया ने मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रु. अनुदान के रूप में देने की घोषणा की. राज्य के अधिकांश मंत्री भी घटनास्थल पर जा पहुंचे.

दुर्घटना से पीड़ित लोगों का अनुभव दिल दहला देने वाला था. उदाहरण के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सी.एम. स्टीफन के साले प्रोफेसर वर्गीज तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वे और उनकी बेटी दुर्घटना में जीवित बच गए हैं. उनका कहना था, "रेलगाड़ी बहुत तेज जा रही थी. जब यह दुर्घटना हुई उस समय हमारा डिब्बा बुरी तरह हिचकोले खा रहा था." उनकी मान्यता है कि ड्राइवर ने उस समय ब्रेक लगाए जब गाड़ी पुल पर ही थी जिसके कारण गाड़ी पटरी से उतर गई. वे कहते हैं कि स्थानीय मछुआरे न आए होते तो वे और उनकी बेटी यकीनन डूब गए होते.

दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक 56 वर्षीया राधा देवी थीं जो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता होने के अलावा क्विलोन के लोकप्रिय लोगों में थीं. पिछले महीने पति की मृत्यु के बाद वे अपना दुख भुलाने के लिए बहन के घर बंगलूर गई थीं और इसी गाड़ी से लौट रही थीं. उन्हें गाड़ी से बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतकों की सूची में कर्नाटक के ऑल-राउंडर क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत खानविलकर भी थे जो राष्ट्रीय टीम में चुने जाने की आशाएं संजोए हुए थे.

हालांकि पुलिस ने इस दुर्घटना में तोड़-फोड़ की आशंका को नकार दिया है पर फिलहाल तय नहीं हो पाया है कि दुर्घटना का कारण क्या था? इस सवाल पर अटकलबाजियों का बाजार इस कारण भी गर्म रहा कि रेल अधिकारियों ने इंजन ड्राइवर टी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

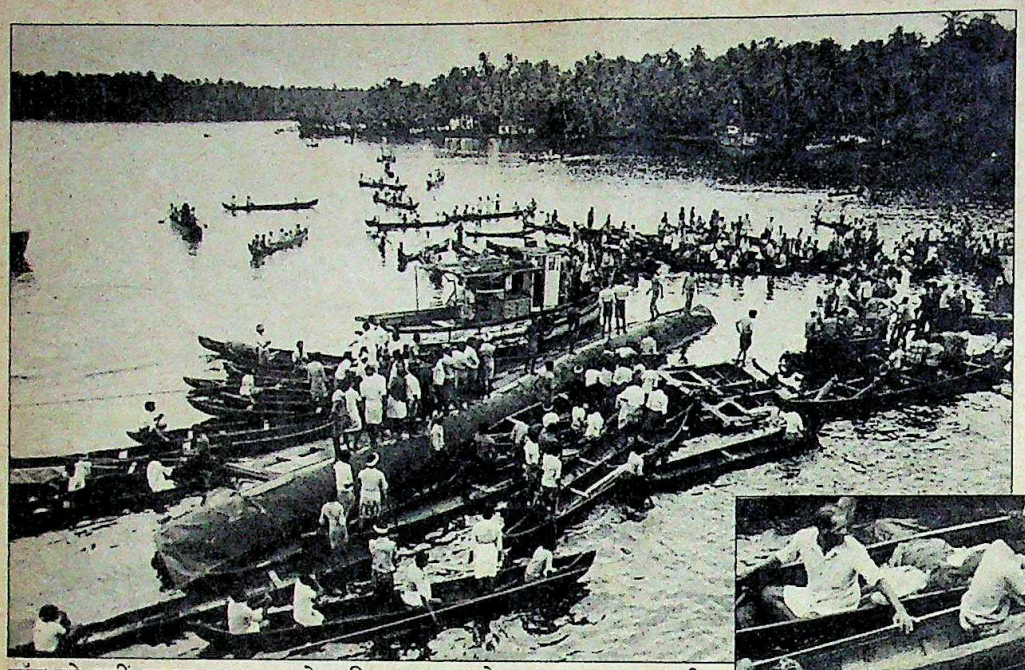

■ स्थानीय लोगों द्वारा नौकाओं और उपलब्ध साधनों से राहत और बचाव कार्य

मधु मंगाड

पॉल को कहीं अज्ञात स्थान पर भेज दिया और किसी को उससे मिलने भी नहीं दिया गया. एक सूत्र के अनुसार पॉल का कहना है कि उसने गाड़ी के पटरी से उतरने के बाद ही ब्रेक लगाए.

जिस पुल पर दुर्घटना हुई वहां पटरी के स्लीपर बुरी तरह उखड़े हुए थे; पटरियां बुरी तरह तुड़-मुड़कर झील में झुकी हुई थीं और पुल पार करने के लगभग 100 मीटर बाद इंजन के पहिए लकड़ी के शहतीरों को चीरते हुए निकल गए थे. ऐसी अस्पष्टता की हालत में राहत कार्यों के दौरान ही राजनीति के लंबे होते साये दिखाई देने लगे थे. केरल के खेल और युवा मामलों के मंत्री, नीललोहितादास नाडर ने जो राज्य के रेलवे संबंधी मामलों को भी देखते हैं, घटनास्थल पर ही टिप्पणियां कीं, "न तो पटरियों की कोई खास देखरेख की जाती है और न ही इस गाड़ी में लगाए जाने वाले डिब्बे ही यात्री ढोने योग्य हैं."

नाडर का दावा है कि गाड़ी के डिब्बे दस साल से भी अधिक पुराने हैं. डिब्बों को जोड़ने वाली व्यवस्था को भी त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है. नाडर का कहना था, "इससे पहले भी रेल अधिकारियों से पटरियों की घटिया देखरेख के सवाल पर बात कर चका हूं. मैं उनके ध्यान में त्रिवेंद्रम जाने वाली एक्सप्रेस गाडियों में पुराने पड़ चुके डिब्बों को बदलने का सवाल भी अनेक बार ला चुका हूं."

लेकिन दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक के. वी. बालकृष्णन का कहना है कि यह एक 'असामान्य दुर्घटना' है. पटरियों के रखरखाव के सवाल पर नाडर की टिप्पणी से भी कई अधिकारी सहमत नहीं हैं. यह बताते हुए कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य का कहना था कि दुर्घटना से केवल 20 मिनट पहले ही बंगलूर जाने वाली 25-अप गाड़ी उस पुल से सुरक्षित गुजरी थी.

लेकिन रेल अधिकारियों के इन दावों के बावजूद केरल में आम तौर पर पटरियों की देखरेख के मामले में सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन न किए जाने के सवाल पर असंतोष है. तिरुअनंतपुरम-एर्नाकुलम के बीच 221 किलोमीटर लंबे रास्ते पर कई रेलवे पुलों का मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि छठे दशक में उनका निर्माण केवल हल्की किस्म की मीटर-गेज गाड़ियों के लिए ही किया गया था.

1976 में इस इकहरी लाइन को ब्राड-गेज लाइन में बदलने के बाद इस पर यातायात में 10 गुना वृद्धि हुई है. इस मार्ग पर भारी मालगाड़ियों के अलावा एक दर्जन एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां तथा कई पैसेंजर गाडियां चलाई जा रही हैं. यह मात्र संयोग नहीं है कि पिछले लगभग दो साल के दौरान क्विलोन और कोट्टायम के बीच कम-से-कम पांच मालगाड़ियां पटरी से उतर चुकी हैं. इस सवाल पर रेल अधिकारी कोई जवाब नहीं देते.

इस दुर्घटना की विस्तृत जांच की मांग करने वाले नयनार का आरोप है कि रेल विभाग केरल की उपेक्षा करता चला आ रहा है. वे कहते हैं, "रेल विभाग के कुल खर्च का केवल 1.5 फीसदी हिस्सा ही केरल पर खर्च किया जाता है. इस सेक्टर में दोहरी लाइन बिछाने की मांग को बार-बार अनदेखा कर दिया जाता है." नयनार बताते हैं कि रेलवे बोर्ड द्वारा कराए सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस सेक्टर पर सुरक्षित सीमा से अधिक यात्री ढोए जा रहे हैं जो कि खतरनाक बात है.

स्पष्ट है कि इस दुर्घटना को राज्य की मार्क्सवादी सरकार केंद्र पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है. उनके लिए यह राजनैतिक नजरिये से उपयोगी भी है क्योंकि राज्य के लोग भयंकर दुर्घटना के सदमे से अभी भी सहमे हुए हैं.

मानवीय दृष्टि से जहां एक ओर स्थानीय नागरिकों द्वारा यात्रियों को बचाने के लिए तुरंत बचाव कार्य में जुट जाना हृदय को छू जाने वाला है, वहीं एक सच यह भी है बीते पखवाड़े के अंत तक नावों में भर-भरकर आने वाले लोगों ने दुर्घटना स्थल को टूरिस्टों की सैरगाह में बदल दिया था.

—श्रीधर पिल्लै

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शीला दीक्षित

मेहनत से मिला मौका

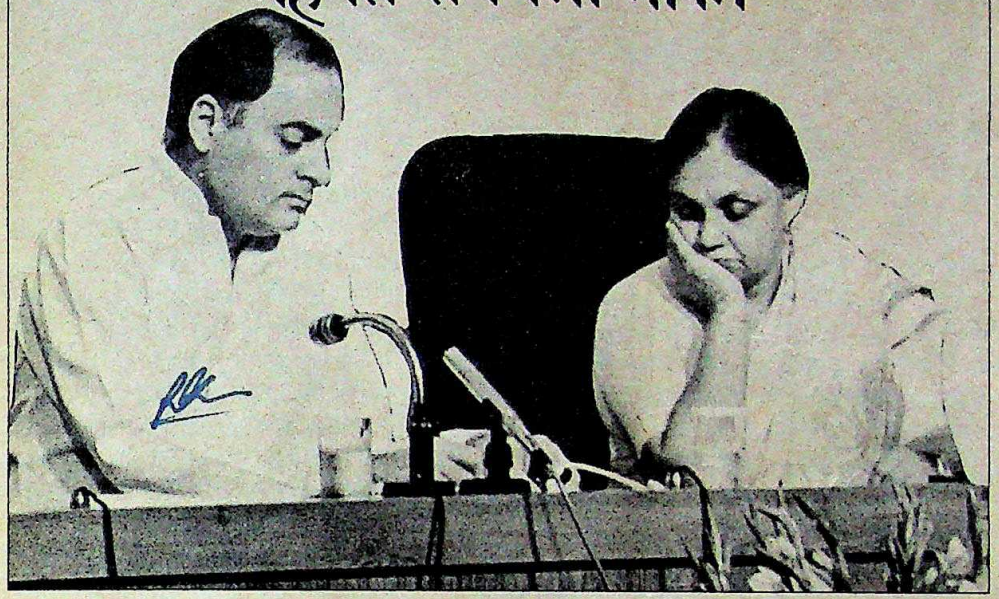

राजीव के साथ शीला दीक्षितः बेमिसाल उत्थान

राजीव गांधी के इर्द-गिर्द तीन महिलाएं हैं. एक तो पत्नी सोनिया जो जहां तक संभव हो हर हाल में (राजनैतिक रूप से भी) पृष्ठभूमि में ही रहना चाहती हैं. दूसरी, कार्यकुशल और विनम्र सचिव सरला ग्रेवाल जो प्रधानमंत्री कार्यालय की वरिष्ठतम अफसर हैं. इसी श्रेणी में नया नाम जुड़ा है 50 वर्षीया शीला दीक्षित का, जिन्हें हाल ही में भारतीय राजनीति की पावनस्थली, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री के रूप में जगह देकर नया इतिहास रचा गया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल के ताजा फेरबदल में दीक्षित की नियुक्ति पर सबसे ज्यादा अटकलें लगीं. वैसे यह उन चंद नियुक्तियों में से भी एक है जिनमें थोड़ी समझदारी दिखी. इस समय तो राजीव को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी भी जो उनके दफ्तर में राजनैतिक मामलों की ठीक-ठीक देखभाल कर सके, राज्यों से मिली सूचनाओं में ताल-मेल बिठा सके, पार्टी के संगठनात्मक मामले निबटा सके, राजनैतिक तौर पर अस्त-व्यस्त ढांचे को संवार सके, नियुक्ति और फेरबदल में प्रधानमंत्री को सलाह दे सके.

पर पिछले पखवाड़े दीक्षित ने 'इंडिया टुडे' को बताया, "मैं सलाहकार की भूमिका अंजाम नहीं दे रही. मेरा काम तो राजनैतिक मामलों के बारे में विभिन्न मत प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है. आगे फैसले वे ही लेते हैं." फिर भी उनकी नियुक्ति के पीछे एक खास राजनैतिक दांव है. मुख्य-मंत्रियों के फेरबदल और राज्यों में नए इंका पदाधिकारियों की नियुक्ति पर विचार-विमर्श के लिए हुई हाल ही की सभी बैठकों से वे करीबी तौर पर जुड़ी रही हैं.

राजनैतिक तौर पर दीक्षित भी अब उतनी ही शक्तिसंपन्न हैं जितने श्रीमती गांधी के जमाने में आर.के. धवन हुआ करते थे. राजनीति तो उन्हें विरासत में ही मिली है. वे इंका के दिग्गज उमाशंकर दीक्षित की पुत्रवधु हैं. हालांकि उनका राजनैतिक जीवन अपेक्षाकृत कम समय का है पर उनमें नए काम को निबाहने की भरपूर क्षमता है. वे कठोर और तेजतर्रार तो हैं ही, कई मौकों पर बहुत ही सपाट शब्दों में अपनी बात कह सकती हैं. कहा जाता है कि वे किसी के रौब में नहीं आतीं, चाहे अगला कितना ही ऊंचा क्यों न हो. बातचीत में भी वे बहुत मुखर हैं जिसका श्रेय कांवेंट स्कूल और मिरांडा हाउस में हुई उनकी शिक्षा-दीक्षा को है.

लेकिन इससे भी बढ़कर, इस नियुक्ति से दीक्षित राजनैतिक कैरियर के उस शिखर पर पहुंच गई हैं जिसे आजकल बेहद शानदार माना जाता है. चार ही साल पहले वे लखनऊ में सिले-सिलाए कपड़े निर्यात करने वाली एक फर्म में बतौर मध्यम दर्जे की एक अधिकारी के रूप में काम करती थीं. उन दिनों उनके आईएएस अफसर पति भी वहीं नियुक्त थे. दीक्षित याद करती हैं, "मुझे दो जगहों का खर्च चलाना पड़ता था. एक नई दिल्ली और दूसरे लखनऊ के घर का. पैसों की सचमुच तंगी थी इसलिए मैंने 1,500 रु. प्रतिमाह पर वस्त्र निर्यात की यह नौकरी कबूल कर ली थी."

तब तक उन्होंने राज-नीति में ठौर तलाशना शुरू कर दिया था. दरअसल राजनीति से उनका परिचय 1969 में ही होने लगा था. इसका श्रेय उनके ससुर को है, जो कांग्रेस के विभाजन के वक्त इंदिरा गांधी खेमे में शामिल हुए थे. इनाम के तौर पर उमाशंकर दीक्षित को कांग्रेस कोषाध्यक्ष का पद मिला. जब 1971 में संस-दीय चुनाव हुए तो शीला दीक्षित ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए चंदा जुटाने के काम में उनकी मदद की. वे कोषाध्यक्ष के दफ्तर में आने वाले ढेर सारे आवेदनों और पत्रों का जवाब देने का भी जिम्मा संभाल रही थीं. इससे भी पार्टी के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क कायम हो गया.

लेकिन पति की नियुक्ति दिल्ली से बाहर होने पर उनके राजनैतिक कैरियर की डोर अचानक टूट गई. पर इससे उनकी या उनके ससुर की राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं मंद नहीं हुईं. ससुर की सिफारिश पर उन्हें दिसंबर 1984 के चुनावों में उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का टिकट दिया गया. उन्होंने बड़ी आसानी से यह चुनाव जीता. फिर राजनैतिक परिधि में आकर वे ऊंचाइयां ही चढ़ती गईं. 1986 में सांसद के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही उन्हें संसदीय राज्यमंत्री बना दिया गया. इस काम को उन्होंने बड़ी कुशलता से निभाया भी.

दरअसल मंत्री पद के माध्यम से ही पार्टी के आला स्तर पर उनकी पहुंच हो गई. इस दौरान उनका एक प्रमुख काम लोकसभा में बहस के दौरान इंका के संभावित वक्ताओं की फेहरिस्त बनाना भी था. अपनी हैसियत निखारने के लिए उन्होंने यह काम बड़ी चुस्ती से किया. लोकसभा में हर बहस के दौरान वे सांसदों को पुर्जियां बांटने के लिए एक पंक्ति से दूसरी में घूमतीं जिनमें सदस्यों द्वारा बहस में उठाए जाने वाले मुद्दों का उल्लेख होता. दरअसल उनकी इस सक्रियता के मद्देनजर ही उन्हें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'पुर्जी मंत्री' कहा जाने लगा था.

उनकी मेहनत सही समय पर रंग लाई. उनके काम से प्रभावित होकर राजीव ने उन्हें स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ और नेहरू जन्मशती के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बना दिया. इससे वे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के साथ ही अनेक वरिष्ठ पार्टी नेताओं और इंका मुख्यमंत्रियों के सीधे संपर्क में आ गईं.

दीक्षित ने एक और कला का बखूबी प्रदर्शन किया जिसकी इंकाई संस्कृति में सबसे ज्यादा कीमत है. वह है प्रधानमंत्री के प्रति पूर्ण वफादारी. बोफोर्स घोटाले के कारण जब राजीव-विरोधी अभियान अपने चरम पर था, वे प्रमुख पत्रकारों को अपने यहां बुलाकर बड़े जोरदार ढंग से सरकारी दृष्टिकोण सामने रखतीं. संसद की लॉबी में भी वे पार्टी सहयोगियों को प्रधानमंत्री के पक्ष में अधिक आक्रामक रवैया अपनाने के लिए अक्सर उत्साहित करती दिखतीं.

जाहिर है उनकी ताजा नियुक्ति वफादारी और मेहनत दोनों का ही इनाम है. लेकिन इस काम में उनकी कड़ी परीक्षा भी होने वाली है. उन पर बड़ा दायित्व तो यही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में पार्टी नेताओं की पहुंच ज्यादा आसान हो और उसे राजीव को अलग-थलग रखने वाले निहित स्वार्थों के पंजों से छुटकारा दिलाया जाए. पिछले दो साल में यह साफ हो गया था कि गोपी अरोड़ा सरीखे कुछ प्रमुख अफसरशाह ही ऊंचे स्तर पर राजनैतिक फैसले लेने में शामिल रहते हैं. यहां तक कि मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री के सहयोगियों के साथ राजनैतिक सलाह-मशविरे करने पड़ते थे.

अब इस नाजुक राजनैतिक संतुलन को बहाल करने की जिम्मेदारी दीक्षित पर होगी. लेकिन इसमें उनका बेमिसाल उत्थान ही आड़े आ सकता है क्योंकि उनके इस उत्थान को देखकर कइयों की छाती ईर्ष्या से जल उठी है और उनके दुश्मनों की तादाद भी बढ़ी है. फिर अब यह तय करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है कि किस नेता को राजीव से मिलना है और किसे नहीं. इंका में एक हलका पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त किए गए संसदीय सचिवों की विफलता का मुद्दा उछालता आया है. लेकिन दीक्षित पर इससे खास असर नहीं पड़ने वाला. दरअसल उन्होंने पहले ही जता दिया है कि मौका मिलने पर वे उसे हाथ से नहीं जाने देतीं. जो लोग उनकी राजनैतिक मौत देखने को आतुर हैं उन्हें शायद अभी लंबा इंतजार करना पड़े. —प्रभु चावला

केरल

मत्स्य पुराण

मशीनी नौकाओं का विरोध

केरल की मार्क्सवादी सरकार धर्मसंकट में फंस गई है. एक तरफ एक लाख परंपरागत मछुआरे हैं जो मांग कर रहे हैं कि बरसात का मौसम झींगा मछलियों के प्रजनन का समय होता है इसलिए समुद्र में मशीनी नौकाओं से मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाए. दूसरी तरफ है ताकतवर मंत्री जो इस तरह मछली पकड़ने का काम जारी रखने पर तुले हैं.

केरल स्वतंत्र मत्स्य थोडियाली महासंघ के मछुआरों ने एक ईसाई पादरी फादर थॉमस कोचेरी के नेतृत्व में 10 जून से समुद्रतटों पर मशीनी नौकाओं के इस्तेमाल के खिलाफ धरना देना शुरू किया. आखिरकार कोचेरी ने जब राज्य सचिवालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी तो सरकार ने 25 जून को हथियार डाल दिए.

मशीनी नौकाओं पर प्रतिबंध तो लगा लेकिन दक्षिण केरल के नींडकरा इलाके को इसके दायरे से अलग रखा गया. इसके पीछे सरकारी तर्क यह है कि कारिक्कडी नस्ल की झींगा मछलियां बरसात के दौरान सिर्फ यहीं पाई जाती हैं जिन्हें सिर्फ मशीनी नौकाओं से ही पकड़ा जा सकता है. लेकिन आम धारणा यह है कि सरकार सिंचाईमंत्री, विप्लवी समाजवादी दल (आरएसपी) के बेबी जॉन को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है. जॉन 30 सालों से चवरा विधानसभा क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं. इसी हलके में नींडकरा इलाका पड़ता है और यहां से समुद्री खाद्य का आयात सबसे अधिक होता है.

सरकार के इस निर्देश पर अखिल केरल मशीनीकृत नाव मालिक संघ ने कोचिन में प्रदर्शन किया और उसके बाद नींडकरा को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 1981 में भी सरकार के ऐसे ही एक निर्देश को हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण बताकर रद्द कर दिया था. उस समय भी जॉन मंत्री थे. कोचेरी कहते हैं कि फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है पर यदि अदालत सरकारी निर्देश को रद्द कर देती है तो वे नींडकरा समेत सभी जगहों पर बरसात के मौसम में मशीनी नौकाओं पर पाबंदी लगाए जाने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे.

दरअसल लड़ाई मछली मारने के हक की है. इसमें एक तरफ 3,500 मशीनीकृत नावों के मालिक हैं तो दूसरी तरफ 26,000 डोंगियों तथा मोटर लगी छोटी 9,500 नावों के मालिक. बारिश के मौसम में यह झगड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इस मौसम में बड़ी संख्या में झींगा मछलियां (प्रॉन) प्रजनन के लिए किनारे आ जाती हैं. मछुआरों का कहना है कि मशीनी नौकाएं इसी मौके पर अपने बड़े जालों से झींगा मछलियों को पकड़ लेती हैं. इस समय वे काफी छोटी होती हैं. इससे उनके प्रजनन पर असर पड़ता है.

केरल में झींगा मछली राजस्व का एक बड़ा स्रोत है. हर साल केरल से कुल 400 करोड़ रु. के समुद्री खाद्य के आयात में से करीब आधे से अधिक हिस्सा झींगा का ही होता है. आंकड़ों से पता चलता है कि झींगा की पकड़ में काफी गिरावट आई है. 1980 में जब पहलेपहल मशीनी नौकाओं का इस्तेमाल शुरू हुआ तब कुल पकड़ 51,600

कार्टून: अजीत नैनन

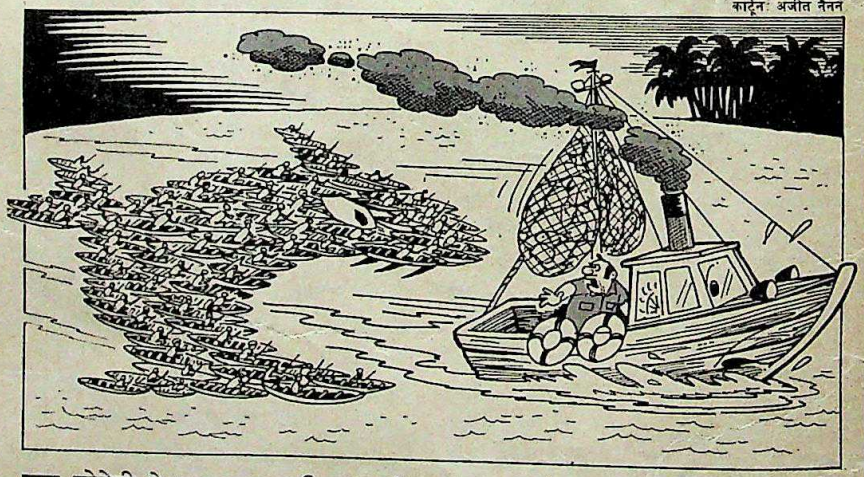

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टन थी लेकिन पिछले साल यह सिर्फ 28,100 टन ही रही. एक समुद्रीय वैज्ञानिक का कहना है कि यह स्थिति ज्यादा मछली पकड़ने से ही बनी है. झींगा की पकड़ में गिरावट आने से मशीनी नौकाओं के मालिक अब बांगड़ा और सार्डीन मछलियां पकड़ने लगे हैं. ये मछलियां आम तौर पर परंपरागत मछुआरों की पकड़ हुआ करती थीं. इससे भी तनाव बढ़ रहा है.

गैर-मशीनीकृत नौकाओं के मालिकों की दूसरी भी समस्याएं हैं. दो दशकों के अंदर उनकी कुल पकड़ तीन लाख टन से घटकर पिछले साल 1.9 लाख टन हो गई. लेकिन मशीनीकृत नौकाओं की पकड़ की मात्रा 1.2 लाख टन हो गई है.

सचाई तो यह है कि मछुआरों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस समस्या से निपटने के लिए तीन साल पहले बनाए गए कलवार आयोग के मुताबिक सिर्फ 1,150 मशीनीकृत नोकाएं, 2,700 मोटर लगी नौकाएं और 20,000 डोंगियां ही होनी चाहिए. लेकिन मशीनी नौकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है.

एक और विकल्प यह है कि दूसरे कई देशों की तरह यहां भी मछली मारने के दिन तय किए जाएं. लेकिन अखिल केरल मशीनीकृत नाव मालिक संघ के मुखिया के.जे.पॉल का कहना है कि ऐसा वहीं संभव है जहां सिर्फ एक ही तरह की मछली पाई जाती हो. केरल में ऐसा नहीं है. लेकिन जॉन बताते हैं कि परंपरागत मछुआरों की झींगा पकड़ने की क्षमता अधिक नहीं है और मशीनी नौकाएं करीब 94.4 फीसदी झींगा मछलियां पकड़ लेती हैं. उनका यह भी कहना है कि झींगा मछलियों को बड़ी संख्या में बारिश के मौसम में ही पकड़ा जा सकता है.

लेकिन आंकड़े झींगा की पकड़ में गिरावट आने की एक अलग ही कहानी कहते हैं. पॉल समेत अधिकांश लोग सरकार की इस धारणा की खिल्ली उड़ाते हैं कि कारिक्कडी मछली सिर्फ नींडकरा के आस-पास ही पाई जाती है. उनका कहना है कि अकेले कोचिन में इसकी पकड़ 14 करोड़ रु. से अधिक की होती है.

पॉल बताते हैं कि कई सालों से नाराज मछुआरों ने अपनी हदों में घुसपैठ करने वाली 137 मशीनी नौकाओं को जला डाला है. समुद्र के किनारे से 10 किलो-मीटर दूरी तक मशीनीकृत नाव से मछली मारने पर पाबंदी है. इस साल जलाई गई मशीनी नावों की संख्या 13 है. यह इस उद्योग के लिए अशुभ संकेत लगता है.

—श्रीधर पिल्लै

मध्य प्रदेश

सांसत में सांसद

जमीन लेने का मामला रंग लाया

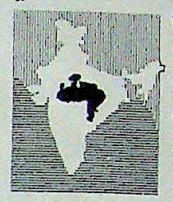

पचमढ़ी में अपनी एक और शाखा न खोलने के दून स्कूल के फैसले से जिस शख्स को सबसे ज्यादा खुशी हुई है वे हैं इंका सांसद और इंका सेवा दल (जिसके अध्यक्ष राजीव गांधी हैं) के उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा. नए दून स्कूल से नीखरा के आवासीय स्कूल नालंदा विद्यापीठ के विकास और विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं खटाई में पड़ जातीं.

लेकिन नीखरा और कई

विवादास्पद स्कूल (नीचे); और नीखराः आरोपों के घेरे

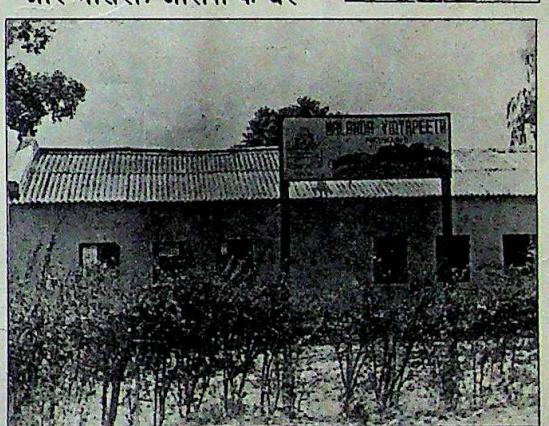

समस्याओं से घिरे हुए हैं. हाल ही में विधानसभा में उन पर अपने स्कूल के लिए 18 एकड़ कीमती जमीन हथियाने का आरोप लगाया गया. यह जमीन नीखरा को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने जनवरी 1986 में दी थी. लेकिन मुख्यमंत्री पद पर अर्जुन सिंह की वापसी के बाद लगता है कि दो साल पुराने इस स्कूल के प्रति नई सरकार का रवैया उदार नहीं है.

सबसे बड़ी अड़चन नालंदा विद्यापीठ को दी गई जमीन और इमारतों के मूल्यांकन को लेकर है. इन इमारतों का निर्माण केंद्रीय तिब्बतीय स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) ने 1966 में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए किया था. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) जहां इन इमारतों की कीमत 6.2 लाख रु. आंकता है, राज्य के लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के अनुमान के अनुसार इनकी कीमत 4.2 लाख रु. से ज्यादा नहीं. सीटीएसए ने इमारतों की कीमत कम आंके जाने का विरोध किया है. लिहाजा दोनों निर्माण विभागों से साझा तौर पर इनका मूल्यांकन करवाने की कोशिशें की जा रही हैं.

नीखरा पर जमीन हासिल करने के तरीके को लेकर भी गंभीर आरोप हैं. पचमढ़ी में जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है. लेकिन मंत्रिमंडल से मंजूरी लिए बिना ही नालंदा शिक्षा संस्थान को यह जमीन दे दी गई. इस क्षेत्र से भाजपा विधायक मुरलीधर माहेश्वरी का आरोप है कि "नीखरा को उपकृत करने के लिए वोरा ने मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं समझी."

नीखरा का कहना है कि उन्होंने 'उन्हीं शर्तों' पर आवेदन किया था जिन पर सीटीएसए को जमीन दी गई थी. पचमढ़ी के उप जिला मुख्यालय, पिपरिया के रिकार्ड के अनुसार सीटीएसए को 16,055 रु. और 401 रु. के वार्षिक पट्टा किराए पर जमीन दी गई थी. यह रकम 1964 में जमीन की अनुमानित कीमत की एक चौथाई ही थी. राजस्व अधिकारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण इस इलाके में जमीन मिलनी मुश्किल है. पर नीखरा के संस्थान को चार लाख रु. की जमीन सिर्फ 16,000 रु. में ही मिल जाएगी. इस पर नीखरा कहते हैं, "इसमें बुराई क्या है? सरकार तो शैक्षिक संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन देती ही है."

लेकिन नीखरा के विरोधियों का कहना है कि नालंदा विद्यापीठ को ऐसी सरकारी रियायतों की जरूरत नहीं है क्योंकि यह स्कूल धनी-मानी तबके के बच्चों के लिए है. यहां एक बच्चे को पढ़ाने का मासिक खर्च तकरीबन 1,000 रु. है.

इसके अलावा इस स्कूल का संचालन एक पारिवारिक न्यास करता है जिस पर सरकार का कोई काबू नहीं. खुद नीखरा इस न्यास के अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी, एक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिश्तेदार, छह दोस्त और समर्थक इसके सदस्य हैं. इनमें न्यास के उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद तिवारी और स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं. तिवारी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में सहायक निरीक्षक भी हैं. कहा जाता है कि स्कूल की स्थापना के पीछे उन्हीं का विभाग था. स्कूल खुलने के तुरंत बाद उनका तबादला पचमढ़ी हो गया था. सरकारी नौकर होने के बावजूद वे स्कूल के परिसर में ही रहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं.

लेकिन अर्जुन सिंह की वापसी के बाद आशंका व्यक्त की जा रही है कि नीखरा अब शायद वोरा की स्वीकृत शर्तों पर जमीन नहीं ले पाएंगे. नीखरा समझ गए हैं कि राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कई बार भारी भी पड़ जाता है.

—नरेंद्र कुमार सिंह, पचमढ़ी में

आंध्र प्रदेश

ऊंचाई पर अंकुश

मुकदमा आखिर रंग लाएगा

गगनचुंबी इमारतों पर नियंत्रण किसी भी शहर के लिए एक ज्वलंत मुद्दा हो सकता है. पर हैदराबाद में इसकी कुछ ज्यादा ही सुगबुगाहट है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में फिलहाल एक मामला चल रहा है जिसके दूरगामी कानूनी नतीजे निकलेंगे. एक तरफ भवन निर्माता हैं जिन्हें लगता है कि निर्माण संबंधी कानून उन्हें उनके निवेश का 'जायज' फायदा उठाने से रोकता है. दूसरी ओर पर्यावरणवादी और हैदराबाद प्रेमी हैं जो मानते हैं कि इस तरह का विकास यहां के बाशिंदों की बेहतरी के खिलाफ है.

हाईकोर्ट में यह मुकदमा अप्रैल में दर्ज हुआ और 22 जून को न्यायमूर्ति वाई.वी. अंजनेयुलु के सामने सुनवाई के लिए आ गया. दोनों पक्ष अपना-अपना मत अदालत के समक्ष रखने की तैयारी में लगे हुए थे कि पिछले पखवाड़े हैदराबाद नगर निगम हैदरगुडा इलाके में हरकत में आ गया. 5 जुलाई को निगम ने वहां बन रही एक इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल की कंक्रीट की छत गिरा दी और नियम तोड़कर बनाई गई एक बहुमंजिली इमारत की चारदीवारी पर बुलडोजर चला दिया. निगम आयुक्त हरिशंकर ब्रह्मा कहते हैं, "भवन निर्माता किसी को कुछ नहीं समझते और उम्मीद करते हैं कि वे चाहे जो कर लें, कोई उनका कुछ नहीं कर सकेगा."

हैदराबाद शहर को हलकों में बांटने और बहुमंजिली इमारतों पर नियंत्रण के नियम 1981 में हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के फैलाव (क्षेत्रफल: 1,554 वर्ग किलोमीटर; आबादी 35 लाख) के सर्वेक्षण के बाद बनाए गए. प्राधिकरण ने एक शहरी कला आयोग भी बनाया जिसमें कलाकारों, वास्तुशिल्पियों और शहर के सौंदर्यपूर्ण विकास में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को शामिल किया गया. हालांकि इन लोगों ने कई सुझाव दिए लेकिन राज्य की सरकार ने असरदार भवन निर्माता लॉबी के दबाव में उन्हें ठुकरा दिया.

पर 1981 के फैसले से ऊंची इमारतों (चार या उससे ज्यादा मंजिलों वाली) की

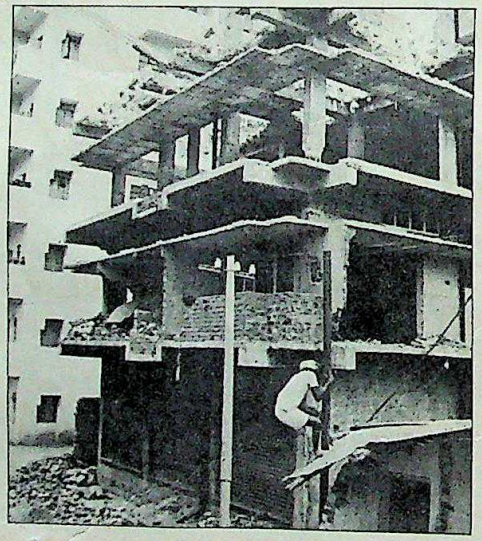

बुलडोजरों का विरोध

वृद्धि पर नियंत्रण के कुछ मार्गनिर्देश जरूर तैयार हो गए. पर भवन निर्माता निर्माण के परमिट लेते रहे और बेशर्मी से नियमों को तोड़ते रहे. इसके अलावा वे सरकार में बैठे लोगों को घूस देकर, उन पर दबाव डालकर अपने खिलाफ आरोपों को दबाने के लिए विशेष इजाजत—जिसे वे "छूट" कहते हैं—हासिल करते रहे. लेकिन उनके ये हथकंडे नाकारा हो गए तो उन्होंने नगर निगम और राज्य सरकार को अदालत में खींच लिया.

पर अब बदलाव की हवा चल पड़ी है. 6 जुलाई को अंजनेयुलु ने निगम को निर्देश दिया कि वह डॉ. वसंत बावा को शहर के बंजारा हिल इलाके में कुछ निर्माताओं को दिए गए परमिटों के तमाम दस्तावेज देखने की इजाजत दे. पूर्व आईएएस अफसर डॉ. बावा शहरी विकास अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं. अदालत ने यह निर्देश बांबे एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप और हैदराबाद के तीन जाने-माने नागरिकों—नई दिल्ली में आवास और शहरी विकास सचिव रह चुके एन.जे. कामथ (66), ब्रिगेडियर जी.एम. सईद (73), भारतीय नौसेना में केप्टन रहे एन.एस. तैयबजी (75) और बावा की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया.

याचिका दायर करने वालों की मांग है कि हाईकोर्ट पिछले पांच साल में नगर निगम द्वारा दिए गए तमाम निर्माण परमिटों की जांच के लिए समिति नियुक्त करे जिसमें इतिहास, वास्तुशिल्प, शहरी नियोजन और सौंदर्यशास्त्र विषयों के माहिर हों. याचिकाकर्ता यह भी चाहते हैं कि निगम बंजारा हिल इलाके में तीन मंजिल से ऊंची इमारतें बनाने की इजाजत न दे.

वैसे नगर निगम ने अंधाधुंध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए चार महीने पहले राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि बंजारा हिल इलाके में तीन या ज्यादा मंजिलों वाली सभी इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी जाए. ब्रह्मा कहते हैं, "हमने यह भी सुझाव दिया था कि इन इमारतों को एक निश्चित समय के बाद अल्ट्रासोनिक ढंग से जांचा जाए कि कहीं उनमें दरारें तो नहीं आ गईं. ये इमारतें सर्वथा असुरक्षित हैं."

कायदा-कानून ताक पर रखने वाले भवन निर्माताओं ने इमारतों में आपात निकास और जरूरी संख्या में लिफ्ट जैसे आधारभूत इंतजाम भी नहीं किए हैं. जाने-माने कलाकार और हैदराबाद शहरी कला आयोग के सदस्य लक्ष्मण गौड़ कहते हैं, "हैदराबाद की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक ये इमारतें अब कलंकित हो गई हैं."

कुछ दूसरे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इन इमारतों की सबसे ऊंची मंजिलों में आग पर काबू पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है और हैदराबाद में आने या जाने के लिए उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए भी परेशानी खड़ी हो रही है. दुखद यह है कि इन इमारतों में रहने वाले अभी इन खतरों को ठीक से नहीं समझ रहे. पर यह तय है कि अदालत में चल रहा मामला आने वाले महीनों में विवाद को और हवा देगा.

—अमरनाथ के. मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता हेतु पहला नाम

प्रकाशन का गौरवपूर्ण चौथा वर्ष

प्रतियोगिता विकास

प्रतियोगी ज्ञान-विज्ञान की नवीनतम सूचनाओं का स्वर्णिम साधन

अगस्त १९८८

वार्षिकांक

अब सर्वत्र उपलब्ध है

बहुत सारी ज्ञानवर्द्धक सामग्री
मूल्य मात्र १२-०० रुपये

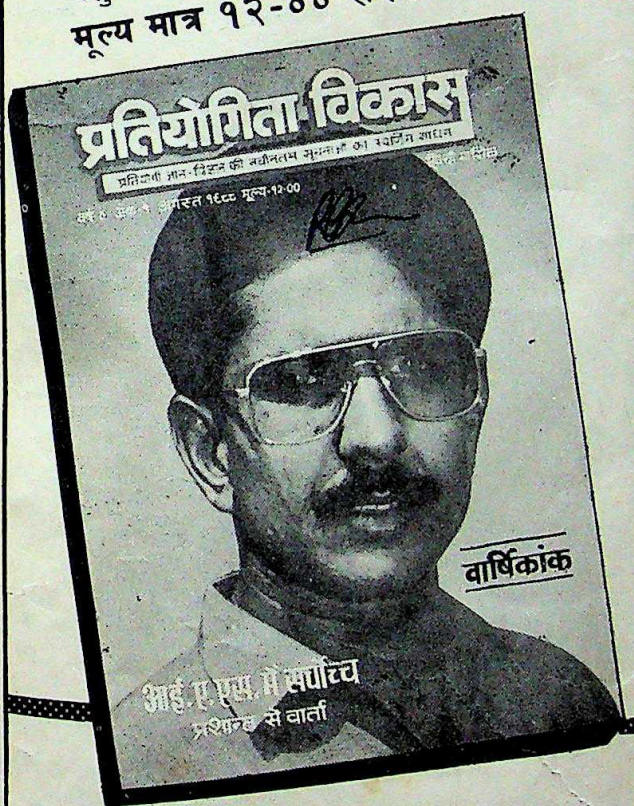

वार्षिकांक के मुख्य आकर्षण

- **आमुख कथा-**
  आई. ए. एस. में सर्वोच्च प्रशान्त से भेंटवार्ता
- **प्रमुख लेख-** सुल्तानतः एक परिचय
  • श्रमण संस्कृति • भारत में शिक्षा के ४० वर्ष
  • भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण
  • श्री लंका की जातीय समस्या • विदेशी कर्ज का मायाजाल • मास्को शिखर वार्ता
- **परीक्षा सामग्री-**
  भारतीय वन सेवा परीक्षा • बी. एड. परीक्षा।

साथ में पूर्ववत सभी स्थायी स्तंभ :- आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचार, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेलकूद, समाचार समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, प्रादेशिकी, अपना देश-प्यारा प्रदेश, विश्व एक-देश अनेक, एक नजर में, सामूहिक वाद-विवाद, जिनके हम ऋणी हैं, निबंध प्रतियोगिता, ये भी जानिये, प्रतियोगी परीक्षा परिचय, आप पूछें-हम बताएं, सामान्य हिन्दी, रोजगार के अवसर, भारतीय संविधान, व्यक्ति परिचय, महत्वपूर्ण तिथियाँ, अंग्रेजी सुधारिये, वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान, वैज्ञानिक कारण, English Essay and Letteer इत्यादि-इत्यादि।

व्यक्तित्व निर्माण, भविष्य निर्माण और व्यावहारिक सफलता की पक्षधर

प्रतियोगिता विकास (मासिक), १/११, साहित्य कुंज, आगरा-२८२००२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Indiaads

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार

तने तमंचों की तान

मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के शीतयुद्ध से राजनैतिक संकट

राज्य विधानसभा में पहली बार कदम रखते ही रंग जमा देने का मंसूबा बांध रखा था मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने. लेकिन अचानक ही जैसे किसी राजनैतिक बवंडर ने उन्हें आ घेरा. पिछले पखवाड़े वे इस झंझावात से बुरी तरह परेशान नजर आए.

इस बवाल की जड़ में था आजाद और विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा का वर्षों पुराना झगड़ा. आजाद और झा दोनों ही भागलपुर के हैं. बवंडर उठा हिंदी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के पटना संस्करण के 27 जून अंक में पहले पेज पर छपी एक रपट से. विधानसभा सत्र शुरू हुए अभी तीन ही दिन बीते थे. रपट में विधानसभा के छपे हुए प्रश्न पत्र से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक प्रश्न निकाले जाने को 'जालसाजी' बताया गया था. यह प्रश्न माकपा विधायक उमाधर सिंह ने पूर्व उद्योगमंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह के बारे में 19 फरवरी 1986 को अल्पकालिक नोटिस पर पूछा था. प्रश्न मंजूर भी हो गया और छप भी गया. लेकिन झा ने उसे अपने इस तर्क से हटा दिया था कि मंत्री के खिलाफ अपने आरोप पर कोई सबूत देने में उक्त सदस्य नाकामयाब रहे हैं.

इस रिपोर्ट के छपने के दूसरे ही दिन विधानसभा में लोकदल विधायक दल के नेता लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में लोकदल विधायकों ने सदन में भारी रोष प्रकट किया. लोकदल के हिंद केसरी यादव ने तो विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग तक की क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पिछले सत्र से ही लटका पड़ा है. भारी हंगामे के बीच अध्यक्ष ने यादव को सदन से निकाले जाने का आदेश दिया. बाद में अध्यक्ष का कहना था कि उन्होंने विधायक उमाधर सिंह से अनुरोध किया था कि वे 10 मार्च '86 तक अपने आरोपों से संबंधित दस्तावेज पेश करें. उमाधर सिंह से बात करने के बाद दस्तावेज के अभाव में प्रश्न को स्थगित कर दिया गया था.

जब झा ने इस रपट पर नाराजगी भरी टिप्पणी की कि यह सदन और अध्यक्ष की अवमानना है तो अखबार ने पहले पेज पर स्थानीय संपादक (दीनानाथ मिश्र) के हस्ताक्षर से अग्रलेख छापा. अग्रलेख में कहा गया कि मामला विधायक के सवाल पूछने के अधिकार और सदन की प्रभुसत्ता पर किए गए बर्बर हमले का है. अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया कि उमाधर सिंह ने मंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था, वे तो सिर्फ यह जानना चाहते थे कि मंत्री के खिलाफ कितने आरोप लगाए गए हैं और क्या उनकी कोई जांच हुई है. जांच हुई तो क्या मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट दी गई है.

साफ है कि लड़ाई अखबार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच थी और उन्हीं दोनों में चलती. लेकिन झा को शक हो गया कि रिपोर्ट के पीछे आजाद का हाथ है इसलिए उन्होंने आजाद पर असहयोग करने का आरोप लगा दिया. 1 जुलाई को तो विधानसभा में संवैधानिक गतिरोध की स्थिति ही पैदा हो गई. उस दिन सदन की बैठक कुल नौ मिनट ही चली—भोजनावकाश से पहले तीन मिनट और उसके बाद कुल छह मिनट. विधानसभा अध्यक्ष ने यहां तक कहा, "सदन में बहुमत दल, जिसकी सरकार है, उससे चेयर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वह नहीं मिला... 27 तारीख से लेकर आज तक कभी भी कोई प्रतिक्रिया जो मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद करता था उन्होंने नहीं व्यक्ति की. इस असहयोग के वातावरण में मैं इस कुर्सी की मर्यादा की रक्षा के लिए लाचार हूं."

अखबार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर पूरे हफ्ते सदन में हो-हल्ला होता रहा लेकिन आजाद चुप्पी साधे रहे. रपट छपने के तुरंत बाद वे अध्यक्ष से मिले थे और उन्हें तब तक धैर्य रखने की सलाह दी थी जब तक नई दिल्ली से पार्टी आलाकमान का कोई निर्देश नहीं आ जाता. पर झा इससे संतुष्ट नहीं हुए. वे चाहते थे कि आजाद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की पहल करें. आजाद के समर्थक कहते हैं कि उनका इस रिपोर्ट से कुछ लेना-देना नहीं, पर पूर्व मुख्यमंत्रियों जगन्नाथ मिश्र व बिंदेश्वरी दुबे के समर्थकों को आजाद पर हमला बोलने का अच्छा मौका मिल गया. इनमें से ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री द्वारा उपेक्षित किए जाने और उन्हें अनुशासित करने की मुख्यमंत्री की सख्त कोशिशों से पहले से ही नाराज हैं.

आजाद (बाएं) और झा: तनातनी का दौर

मिश्र के समर्थकों—एस.पी. राय और एच.एच. रहमान—की अगुआई में ये लोग तुरंत ही विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में खड़े हो गए, ताकि यह जाहिर हो सके कि इंका दल में आजाद को कितना कम समर्थन प्राप्त है. 191 इंका विधायकों में से 135 ने अखबार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर दस्तखत करके एक तरह से झा को अपना समर्थन जाहिर कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि इस पचड़े में तटस्थ रहे 23 मंत्रियों और 33 इंका विधायकों के साथ झा अलग-थलग से पड़ गए.

शासक दल के लिए हालात तब और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी बदतर हो गए जब लोकदल विधायक दल के नेता लालू प्रसाद यादव की अगुआई में विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की और विधानसभा भंग करने की मांग की. केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने फोन पर झा और आजाद दोनों से बीत की और उनसे आपसी मतभेद मिटाने को कहा. इसके बाद आजाद भी प्रस्ताव के हक में हो गए और शासक दल ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर दिया.

राज्य विधानसभा में पहली बार कदम रखते ही रंग जमा देने के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के मंसूबों पर पानी फिर गया. अचानक ही जैसे किसी राजनैतिक बवंडर ने उन्हें आ घेरा

इस ताजा अखबार प्रसंग से पहले भी सदन में आजाद को परेशानियां उठानी पड़ी हैं. कुछ दिन पहले 30 विपक्षी सदस्यों ने विधान परिषद भंग करने का एक नोटिस जारी किया था क्योंकि आजाद विधान परिषद के ही सदस्य हैं. इसका मकसद इस विरोधाभास को उजागर करना था कि आजाद को उनकी पार्टी ने उपचुनाव के जरिये विधानसभा में जाने की इजाजत नहीं दी बल्कि विधान परिषद का सदस्य बना दिया. आजाद के कुछ समर्थकों ने माना कि विपक्ष के प्रस्ताव के पीछे झा का हाथ है.

बहरहाल, दोनों के बीच तनातनी जारी रहेगी. इसका प्रमाण एक और घटना से मिलता है. जहानाबाद नरसंहार (देखें इंडिया टुडे, 15 जुलाई) पर विपक्ष ने जब काम रोको प्रस्ताव पेश किया तो आजाद ने बहस पर सहमत होकर उसे एक तरह से निरुत्तर कर दिया. बजट सत्र में ऐसी मांग ठुकरा देना साधारण-सी बात होती. लेकिन जब आजाद ने अपनी बात रखने के लिए 20 मिनट का

सभी फोटो: कृष्णमुरारी किशन

राजभवन की ओर मार्च करते विपक्षी विधायकः उग्र तेवर

समय मांगा तो अध्यक्ष ने उन्हें सिर्फ 12 मिनट का ही समय दिया.

लेकिन आजाद का मुकाबला सिर्फ झा और संयुक्त विपक्ष से ही नहीं है. प्रशासन में सुधार लाने की उनकी कोशिशों से नौकरशाही भी उनके खिलाफ हो गई है. अधिकारियों के खिलाफ उनकी खुल्लमखुल्ला सख्ती से भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला.

इस ब्राह्मण मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप जातिवाद का है. यद्यपि वे इसका खंडन करते हैं, लेकिन नौकरशाह कहते हैं कि यह सिर्फ संयोग ही नहीं है कि जेलों में तैनात किए गए सभी सातों एसपी स्तर के पुलिस अधिकारी ब्राह्मण जाति के हैं. पर आजाद का तर्क है, "अधिकारी तो इस या उस जाति के होंगे ही. सवाल यह है कि जिन्हें तैनात किया गया है वे काबिल और ईमानदार हैं कि नहीं."

और तो और, इंकाइयों ने भी इस मुद्दे पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया है. वे कहते हैं कि मार्च में हुए विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों में कुल 11 में से सात सीटें जो इंका को मिलीं उनमें तीन पर (आजाद समेत) ब्राह्मण उम्मीदवार ही खड़े किए गए. फिर वे कहते हैं कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की नौ सीटें खाली हैं पर आजाद ने सिर्फ एक नाम ही सुझाया है—शिक्षामंत्री नागेंद्र झा का जो मैथिल ब्राह्मण हैं और परिषद में जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है.

आजाद के समर्थकों का दावा है कि ब्राह्मणों की इस गिनती का मकसद सिर्फ आजाद पर चोट करना ही है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सख्त रवैया अपना रखा है. पर सचाई यह है कि मुख्यमंत्री ने उन 25 राजनैतिक नियुक्तियों को रद्द करने के लिए कुछ नहीं किया है जिनके तहत विभिन्न निगमों के अध्यक्ष बने लोगों को मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध हैं. उन पर प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे है. इससे भी बड़ी बात यह कि सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार धड़ल्ले से जारी है. उधर बाढ़ की रोकथाम के मुख्यमंत्री के लंबे-चौड़े वायदों के बावजूद काम अभी भी अधूरा पड़ा है.

आजाद अपने बचाव में कहते हैं कि उन्हें एक ऐसे राज्य का जिम्मा सौंपा गया है जिसमें हर चीज अस्त-व्यस्त थी, चाहे वित्तीय मामले हों या कानून-व्यवस्था के. उनके सलाहकार कहते हैं कि भ्रष्ट राजनीतिकों के खिलाफ वे धीमी कार्रवाई ही कर सकते हैं. चुनाव सिर पर हैं और बहुत ज्यादा नेताओं की नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती.

जगन्नाथ मिश्र ने शुरू में आजाद का समर्थन किया था पर अब वे भी उनके आलोचक हो गए हैं. वे कहते हैं, "उनकी गंभीर कोशिशों के बावजूद उनकी सरकार अभी भी बहुत कुछ कर नहीं पाई है." आजाद अभी भी बिहार की हर गलत चीज को दुरुस्त करने की ठाने हुए हैं, पर अब साफ हो गया है कि यह काम कितना कठिन है. अब उनकी कामयाबी, नाकामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वरदहस्त कब तक उनके सिर पर बना रहता है.

—फरजंद अहमद

अभी एक महीना पहले की बात है कि झा और आजाद के बीच तनाव उभरकर सामने आ गया था. झा ने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए एक पत्रकार सम्मेलन किया और उसमें आरोप लगाया कि आजाद के रिश्तेदार उनके इलाके के हरिजनों को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं. इंका सूत्रों का दावा है कि आजाद उन खतरों के प्रति पूरी तरह सतर्क थे जो झा से उनके मतभेदों की वजह से विधानसभा में खड़े हो सकते थे. कहा जाता है कि पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने इस सिलसिले में झा को बुलाकर उनसे बातचीत भी की थी, फिर भी दोनों का शीतयुद्ध खत्म नहीं हुआ.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिम बंगाल

मजहबी जुनून

सांप्रदायिक सौहार्द्र चकनाचूर

विवादास्पद पूजास्थल से बढ़कर सांप्रदायिकता का जहर फैला सकने वाली जगह और कोई नहीं हो सकती. कई वर्षों से सांप्रदायिक दंगे की लपट से बचे पश्चिम बंगाल में पिछले महीने हजारों मुसलमान 1910 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में चल रही मस्जिद में नमाज अदा करने का हक मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए. इसके बाद जो सांप्रदायिक उन्माद फैला उसमें प्रदर्शनकारियों के 12 विकृत शव (गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार 21) मुर्शिदाबाद जिले के कासिम बाजार में बिछ गए.

इस फसाद के बीज पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में ही पड़ गए थे. तब इंडियन मुस्लिम लीग से संबद्ध पश्चिम बंगाल मुस्लिम लीग ने अपने मतदाताओं से वायदा किया था कि वह उन्हें पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली मस्जिदों समेत तमाम मस्जिदों में नमाज अदा करने का हक दिला देगी.

मतदाताओं की भावनाओं को भुनाने की यह तरकीब काम कर गई. दो दशक बाद एक विधानसभा सीट जीतने से लीग जोश में आ गई. 1793 में मुर्शिदाबाद में मुर्शिद कुली खां की बनाई कटरा मस्जिद पर कब्जा करने के लिए आंदोलन छेड़ने की अपील करने वाले पर्चे उसने बंटवाए.

लीग ने आंदोलन के लिए कटरा मस्जिद को शायद इसलिए चुना क्योंकि मुर्शिदाबाद की तीन लाख आबादी में 57 फीसदी मुसलमान हैं. इसके अलावा चूंकि पड़ोसी बांग्लादेश इस्लामी राज्य घोषित हो गया है इसलिए भी लीग के हौसले बुलंद हो गए हैं. लीग ने राज्य और केंद्र सरकारों को दो ज्ञापन भी दिए. लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला. लीग के महासचिव शहादत अली बताते हैं, "हताश होकर जून के शुरू में हमने चेतावनी दी कि 24 जून को हमें कटरा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए."

राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को अहम उपलब्धि मानने वाले सत्ताधारी वाममोर्चा ने कटरा बस्ती से 24 किमी दूर बहरामपुर जिला मुख्यालय में सम्मेलन बुलाकर लीग की भर्त्सना की. अनौपचारिक शिक्षा राज्यमंत्री मुहम्मद अब्दुल बारी ने लीग को सांप्रदायिक करार दिया और आरोप लगाया कि वह समस्याएं पैदा कर रही है.

दंगा भड़कने के आसार देख कटरा मस्जिद के चारों ओर दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई.

सैबल दास

कटरा मस्जिद की पहरेदारी

मुर्शिदाबाद के कासिम बाजार में धर्मांधता के तांडव के लिए मुस्लिम लीग की कट्टरता और मौकापरस्ती कारणीभूत है. इससे प. बंगाल का सांप्रदायिक सौहर्द्र खतरे में पड़ गया है

जिला प्रशासन ने लीगी नेताओं को बता दिया कि उन्हें कटरा जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. लेकिन कर्बला में नमाज अदा करने और जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने की इजाजत उन्हें है.

नियत दिन को लगभग 35,000 मुसलमान बहरामपुर में आ जुटे. जलसा शुरू होते ही कुछ हजार लोगों ने कटरा का रुख किया. भीड़ का एक उपद्रवी दस्ता मुर्शिदाबाद के पाकिस्तान में (यानी बांग्लादेश में) विलय के नारे लगाता बढ़ चला.

बहरामपुर से 12 किमी दूर कासिम बाजार में इस भीड़ ने दुकानें लूटीं और इमारतों पर पथराव किया. वहीं एक हिंदू पुजारी ने उनसे पूजा करके लौटती महिलाओं के लिए रास्ता छोड़ने की गुजारिश की. इसी दरम्यान वहां स्थानीय नाराज लोग भी आ जुटे तो प्रदर्शनकारी बचाव के लिए भाग निकले. लेकिन इलाके से वाकिफ न होने के कारण वे कोशिश करके भी भाग नहीं पाए. पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं थी. उसे दूसरी जगह दंगा भड़क उठने का अंदेशा था. जिला मजिस्ट्रेट डी.डी. चक्रवर्ती बताते हैं, "जो प्रदर्शनकारी वहां फंस गए उन्हें पीटा गया, हंसिए से अपंग किया गया और आखिरकार मार डाला गया."

वाममोर्चे की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही. पहले इसने इसका दोष पश्चिम बंगाल मुस्लिम लीग और विश्व हिंदू परिषद के मत्थे मढ़ा. बाद में कहा कि इस 'हादसे' के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं. मोर्चे ने पहले वाला आरोप शायद इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उसे एहसास हो गया कि यह प्रदर्शन उसकी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पुरातत्व विभाग के खिलाफ था जो कि केंद्र सरकार का संस्थान है.

लीग ने माकपा को 'निहत्थे और निर्दोष मुसलमानों की हत्या' के लिए जिम्मेदार ठहराया है. लेकिन इतनी मौतों के बावजूद लीग अपनी मांग पर डटी है. अली कहते हैं, "या तो सरकार हमें कटरा मस्जिद में नमाज अदा करने दे या संविधान से धर्म के अधिकार का प्रावधान हटा दे."

लेकिन यह दंगा राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द्र के रिकार्ड पर एक दाग तो बना ही दिया गया है, वह भी तब जबकि पुरातत्व विभाग के नियंत्रण वाली बाकी मस्जिदों के संबंध में भी यही मुद्दा उठाया जाना है. इस नरसंहार से एक बात साबित हो गई है कि विवेक और उन्माद में उतनी ही धुंधली विभाजक रेखा होती है जितनी कि एक ऐतिहासिकस्थल और पूजास्थल में.

—कमलजीत रतन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

नायिका से खफा

पर जयललिता झुकेंगी नहीं

यह संकट में घिरी कोई कन्या है या शिकार की तलाश में निकली बाघिन? पिछले पखवाड़े अन्नाद्रमुक के अपने धड़े पर पूर्ण नियंत्रण जमाने की जद्दोजहद करतीं जयललिता जयराम ने तमिलनाडु की घटनाओं पर निगाह रखने वालों को एक बार फिर चकरा दिया.

इस बार जयललिता को उनकी कट्टर विरोधी जानकी रामचंद्रन से नहीं बल्कि उन लोगों से चुनौती मिली जिन्होंने छह महीने पहले पार्टी में विभाजन के दौरान उनका साथ दिया था. पूर्व वित्तमंत्री वी.आर. नेदुनचेडियन की अगुआई वाले पार्टी के एक गुट ने उनके राजनैतिक फैसलों पर सवालिया निशान लगाए और संगठन का लोकतंत्रीकरण करने, नए पदाधिकारी नियुक्त करने और पार्टी कोष की बारीकी से जांच-पड़ताल करने की मांग की.

नेदुनचेडियन के साथ ही बगावत का झंडा उठाने वालों में दो पूर्व मंत्री पणरुति रामचंद्रन और एस. तिरुनवक्कारसु भी हैं. वे जयललिता की निरंकुश कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं. तिरुनवक्कारसु कहते हैं, "हमारा उनके साथ कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है. हमारा एकमात्र मकसद उन्हें निहित स्वार्थों से बचाना है. जब तक वे हमारी शर्तें नहीं मानतीं, हम नहीं झुकेंगे." असंतुष्टों की शर्तों में जयललिता के अंगरक्षकों को हटाना, सरकार से छुट्टी लेकर उनके निजी सहायक बने किसी नटराजन को बरखास्त करना, कम-से-कम दो पार्टी पदाधिकारियों के नाम से बैंक में एक संयुक्त खाता खोलना और नेदुनचेडियन को पार्टी में कोई वरिष्ठ पद देना शामिल है.

अपने विरोधी के खेमे में संकट का लाभ उठाते हुए जानकी ने असंतुष्टों से अपील की कि वे उनके गुट में लौट आएं. उधर द्रमुक और इंका ने और अधिक असंतोष भड़काने की कोशिश की. द्रमुक जहां अपने विरोधी को कमजोर करना चाहती थी, इंका चाहती थी कि जयललिता उसके संरक्षण के लिए मिन्नत करें.

लेकिन जयललिता 'मिट्टी की माधो' नहीं हैं. यह जानते हुए कि मतदाताओं को आकर्षित करने का करिश्मा उन्हीं में है, उन्होंने जवाबी हमला किया. जानकी गुट पर विजय मिलने से उनका हौसला और बढ़ गया.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मई में पणरुति रामचंद्रन की दिल्ली यात्रा के तुरंत बाद ही झगड़े के बीज पड़ गए थे. जयललिता ने इंका के तरफदार माने जाने वाले रामचंद्रन को दिल्ली में इंका नेताओं से चुनावी रणनीति पर बातचीत करने का काम सौंपा था. उन्हें चुनाव आयोग के सामने अपने गुट को असली अन्नाद्रमुक के रूप में मान्यता देने का दावा भी पेश करना था. रामचंद्रन दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह और दूसरे इंका नेताओं से मिले. मद्रास लौटने पर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें इंका से गठबंधन को अंतिम रूप दिए जाने का दावा किया गया था. उन्हें इस तरह का कोई अधिकार नहीं था, लिहाजा जयललिता ने उनकी खिंचाई कर दी. वह रामचंद्रन से इसलिए भी नाराज थीं कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने उनके गुट का मामला चौपट कर दिया.

लेकिन जिस बात से जयललिता बहुत सटपटाईं वह यह थी कि तीनों पूर्व मंत्रियों ने अगले चुनाव के लिए इंका से बिना शर्त गठजोड़ की कोशिशें शुरू कर दीं. इसी संभावना के मद्देनजर केंद्र विधानसभा चुनाव कराने के समय को लेकर आगा-पीछा कर रहा था.

जयललिता को इसमें अपनी पार्टी को कमजोर करने की साजिश दिखी ताकि इंका उन पर अपनी शर्तें थोप सके. वे कहती आई हैं कि वे इंका को एक-तिहाई विधानसभा सीटें ही देंगी. लेकिन उनके कुछ सहयोगी 40 फीसदी तक सीटें देने को तैयार हैं. जयललिता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जीतने पर इंका को सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा. "मैं ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूं जिससे हम केवल अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना सकें. लोगों ने मुझे नेता माना है. उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है."

इन शेखियों के बावजूद जयललिता अपनी पार्टी के लोगों या इंका के साथ रूबरू लड़ाई नहीं लड़ना चाहतीं. इसलिए उन्होंने नेदुनचेडियन और दूसरे नेताओं के साथ समझौते की कोशिश की. वे खुद कार से नेदुनचेडियन के घर गईं और उन्हें पार्टी में वरिष्ठ पद देने की पेशकश की. उन्होंने नेदुनचेडियन को यह भरोसा भी दिलाया कि वे अब प्रायः पार्टी की बैठकें बुलाया करेंगी. लेकिन दो मुद्दों पर उन्होंने समझौता करने से साफ इनकार किया—पार्टी के कोष पर और इंका से गठजोड़ करने के सवाल पर.

बैठक के बाद जयललिता ने कहा, "इन छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा." लेकिन वे शायद यह कभी नहीं भूल पाएंगी कि इस बार हमला पीछे से हुआ है. —प्रभु चावला, मद्रास में

श्याम टेकवानी

रामचंद्रन (एकदम बाएं) और नेदुनचेडियन के साथ जयललिता

पार्टी के एक शक्तिशाली वर्ग ने नेदुनचेडियन की अगुआई में जयललिता के राजनैतिक फैसलों पर सवालिया निशान लगाए और संगठन के लोकतंत्रीकरण की मांग की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

डबल एजेंट

पाकिस्तान को कई भेद दिए

पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों की नजर में वह आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हिसाब से वह एक तस्कर था. खुफिया एजेंसी रॉ और इंटेलिजेंस के रजिस्टरों में उसे जासूस के नाते भुगतान भी किया जाता था और पंजाब पुलिस की सीआईडी ने तो उसे अपना भेदिया तैनात किया हुआ था. लेकिन पिछले पखवाड़े जब बलविंदर सिंह से गुरदासपुर में पूछताछ की गई तो पता चला कि वह इन सभी फनों में माहिर है और थोड़ा-थोड़ा सब कुछ है. अहम बात तो यह है कि वह एक ऐसा डबल एजेंट था जो पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सैनिक सूचनाएं पहुंचाता था.

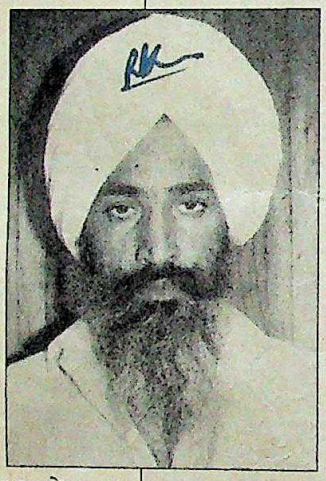

खुफिया एजेंसियों ने अब तक इस कांड से जुड़े 17 भारतीय नागरिकों के नाम हासिल किए हैं जो कई स्थानों पर सक्रिय रहे. लेकिन उन्हें आशंका है कि असली तंत्र का यह केवल एक छोटा रूप ही है

बलविंदर (बाएं); रतनचंद; और सैनी (नीचे)

यह रोमांचकारी कहानी 1971 से शुरू होती है जब रॉ के एक अधिकारी ने उसे पठानकोट में एजेंट नियुक्त किया. पाकिस्तानी सीमा से लगने वाले डेरा बाबा नानक इलाके के निवासी बलविंदर को सीमा के इलाकों की जानकारी की वजह से पाकिस्तान के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए काफी अनुकूल पाया गया. आईबी ने भी उसे 6 साल के लिए नियुक्त कर लिया. इस दौरान वह पंजाब पुलिस की सीआईडी को भी सूचनाएं देता रहा.

लेकिन इस दौरान उन्हें एक बार भी इस बात का भान नहीं हो पाया कि बलविंदर को पाकिस्तानी खुफिया विभाग ने भी अपना एजेंट बना लिया था. जांच के दौरान उसने स्वीकार किया कि तस्करी और सूचनाएं इकट्ठा करने के सिलसिले में एक बार उसकी मुलाकात कुख्यात पाकिस्तानी तस्कर सरवर खां से भी हुई. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले खां ने उसका परिचय कर्नल अख्तर और मेजर अयूब बाजवा से कराया.

शुरू में तो उसने 500 रु. से 1000 रु. प्रति सूचना की दर से सीमावर्ती इलाकों की सामरिक महत्व वाली सड़कों और पुलों वगैरह की जानकारी और फोटो पाकिस्तानियों को उपलब्ध कराए. लेकिन उसके खुफिया कारनामों की असली शुरुआत तब हुई जब उसने नायक सूबेदार रतनचंद को 300 रु. से 500 रु. के भुगतान पर खुफिया दस्तावेज और फाइलें देने के लिए पटा लिया. रतनचंद पठानकोट में नौवें फील्ड आर्डनेंस डिपो में तैनात था और खुफिया फाइलों तक उसकी पहुंच थी. 1984 के अंत तक उसने दो और कर्मचारियों—हेड क्लर्क एम.आर. शर्मा और यूडीसी निशान सिंह सोहल को भी फांस लिया. दोनों के पास खुफिया फाइलें आती रहती थीं. उसने स्थानीय टेलिफोन एक्सचेंज के ऑपरेटर जसपाल सिंह सैनी को भी अपने साथ मिला लिया. वह पुलिस अफसरों की फोन पर बातचीत सुनकर उसे बताया करता.

इस तरह मिली जानकारी को बलविंदर वहां तस्कर के रूप में आए पाकिस्तानी एजेंटों के हवाले कर दिया करता था. दस्तावेजों के इन पुलिंदों में सेना की 29वीं इन्फेंटरी डिवीजन और 39वीं माउंटेन डिवीजन के स्थान और उनकी शक्ति संबंधी जानकारी भी थी. इस जानकारी में भारत-पाक सीमा के साथ-साथ पंजाब और जम्मू-कश्मीर नियंत्रण रेखा पर इन दोनों डिवीजनों के 15-15 हजार जवानों का कंपनी-वार ब्यौरा भी शामिल था. महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू-कश्मीर इलाके में मौजूद तरह-तरह की विशिष्ट टॉस्क-फोर्सों की उपस्थिति के बारे में थी जिसे वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों तक से गुप्त रखा जाता है.

इसकी सबसे बड़ी सफलता थी 1985 में डिपो के एक मेजर के साथ हुई उसकी दोस्ती. इस अधिकारी के माध्यम से उसने पिछले दो साल के दौरान एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं को सेना में क्लर्की और दूसरी नौकरियां दिलाईं.

उससे मिलने वाली खबरें अक्सर भरोसेमंद पाई गईं लेकिन वे सटीक कभी भी नहीं रहीं. मसलन उसने पुलिस को 15 दिन पहले ही बता दिया था कि आतंकवादी कई स्थानों पर बम फेंकेंगे. लेकिन उसने बम विस्फोट के स्थान और समय की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की. अब उसकी पूछताछ से यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के इशारों पर वह जानबूझकर ऐसी सूचनाएं दिया करता था जिससे आतंकवादी खतरा बहुत बड़ा दिखाई दे.

पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने के लिए वह दिल्ली की एक ट्रेवल एजेंसी का इस्तेमाल किया करता था. इस एजेंसी के साथ वह अपना संपर्क 'डॉक्टर' नाम से रखता था. पुलिस ने इस एजेंसी के मालिकों गुरप्रीत सिंह और सुरिंदर कुमार बिल्ला को गिरफ्तार किया है जो पंजाब के कुछ ऐसे आतंकवादियों को बाहर जाने में मदद किया करते थे जिनकी पुलिस को तलाश थी.

इन दिनों बीएसएफ, सेना और रॉ के जासूस इस कांड से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं. अब तक इस सिलसिले में उन्हें ऐसे 17 भारतीय नागरिकों के नाम हासिल हुए हैं जो जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पंजाब में सक्रिय रहे हैं. अधिकारियों को आशंका है कि यह कांड असली खुफियातंत्र का केवल एक छोटा-सा हिस्सा सिद्ध हो सकता है.

—विपुल मुद्गल गुरदासपुर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

मौके पर मार

कर्मचारी हड़ताल रंग लाई

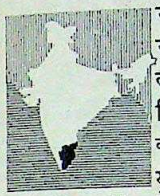

राष्ट्रपति शासन में चल रहे तमिलनाडु के सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए वार करने का शायद यही सबसे उपयुक्त अवसर था. चुनावों की प्रतीक्षा में लगे राज्य के ये कर्मचारी पिछले पखवाड़े अपने दफ्तरों और स्कूलों से लगातार तीसरे सप्ताह बाहर रहे. राज्यपाल पी.सी. अलेक्ज़ेंडर के लिए यह शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है.

हड़ताली कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के

श्याम टेकवानी

अलेक्जेंडर: कड़ी चुनौती

बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं. ज्वाइंट एक्शन काउंसिल (जेएसी) की संचालन समिति के सदस्य पी.एस. सुंदरापांडियन कहते हैं, "हम यह मांग अरसे से कर रहे हैं और 27 मई को हमने हड़ताल का नोटिस भी दिया था. लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना कर दिया."

इन मांगों को अनसुना करने के पीछे अलेक्ज़ेंडर के अपने कारण थे. राज्य के प्रधान सचिव एम.एम. राजेंद्रन बताते हैं, "मांगें मानने का मतलब होगा हर साल 400 करोड़ रु. का खर्च बढ़ाना." इतना खर्च उठाना सरकार के लिए संभव नहीं.

राजनैतिक दल भी बिगड़े हालात का फायदा उठाने के मूड में हैं. अन्नाद्रमुक गुट की नेता जयललिता जयराम का कहना है, "वेतनों में बराबरी की मांग उचित है." द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि का आरोप है कि, "सरकार कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है."

प्रशासन कुछ नरम पड़ा और उसने हर कर्मचारी को 70 रु. मासिक अंतरिम राहत देने की घोषणा की. जिसका मतलब होगा हर साल 80 करोड़ रु. का अतिरिक्त भार.

लेकिन दूसरे दलों का आरोप है कि इंका जानबूझकर हड़ताल को लंबा खिंचवा रही है ताकि चुनावों को स्थगित करने को वाजिब ठहराया जा सके. उन्हें अब यह डर भी सताने लगा है कि चुनावों की घोषणा करने से पहले प्रशासन हड़तालियों का दिल जीतने के लिए उनकी बात मान लेगा.

लेकिन इंका के लिए एक तकलीफदेह बात है. हड़ताली कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग द्रमुक समर्थक है. ऐसे में लगता है कि अगर इंका आखिरी क्षणों में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है तो शायद उसकी मंशा पूरी न हो पाए.

—एस.एच. वेंकटरमनी

पंजाब

सुलह की कोशिश

बरनाला की समझदार पहल

सुबह का भूला मानो शाम को घर लौट आया. 1987 के शुरू में सिख पंथ से निकाले जाने के करीब डेढ़ साल के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने मुख्यग्रंथियों से सुलह की पेशकश करके राजनैतिक बियाबान से उबरने की कोशिश की है.

पिछले पखवाड़े जब बरनाला अकाल तखत के सामने अपनी उन 'गलतियों' के लिए 'बिना शर्त' माफी मांगने आए, जिनकी वजह से उन्हें पंथ से निकाला गया था तो उन लोगों को भी ताज्जुब हुआ जो अकाली राजनीति में अचानक आने वाले मोड़-घुमावों की पूरी जानकारी रखते हैं. माफी मांगने के बाद स्वर्णमंदिर परिसर के एक कमरे में बरनाला और पांचों मुख्यग्रंथियों के बीच दो घंटे तक गुप्त बातचीत हुई. ग्रंथियों ने अभी बरनाला के अनुरोध पर अपना फैसला नहीं सुनाया है. पर ऐसे संकेत हैं कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री से सहानुभूति है.

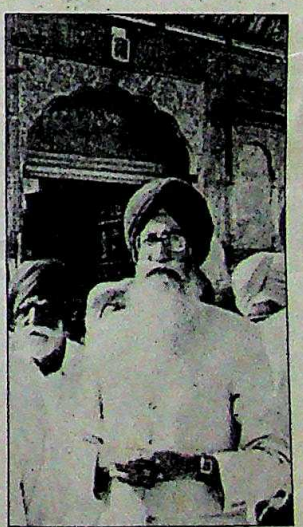

बरनाला: वापसी की कोशिश

अकाली राजनीति के प्रमुख खिलाड़ी बताते हैं कि यह सहानुभूति अकारण नहीं है. जाहिर है, शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति के कई प्रमुख सदस्यों ने ग्रंथियों से बरनाला को क्षमादान देने के लिए कहा था. दरअसल इस चाल के पीछे पूर्व कृषिमंत्री अमरिंदर सिंह का हाथ है.

अगर बरनाला को किसी तरह माफी मिल जाती है तो उनके फायदे की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि इस समय अकाली राजनीति गुटबंदी की शिकार है. मसलन इस समय मुख्यग्रंथियों के तीन समूह हैं. इसके अलावा प्रबंधक कमेटी और एकीकृत अकाली दल में कम-से-कम चार गुट हैं और ये सभी सत्ता के लिए होड़ लगाए हुए हैं.

पिछले पखवाड़े इन गुटों के बीच की लड़ाई नई बुलंदियों पर पहुंच गई और लगभग हर गुट प्रतिद्वंद्वी उग्रवादी संगठनों का समर्थन मांगने निकल पड़ा. इससे पूरी तरह उलझाव पैदा हो गया.

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धींगामुश्ती से बरनाला को एक नई उम्मीद जगी. बरनाला के पास कई दुखी अकाली राजनीतिकों के पहुंचने से उन्हें अचानक कई नए समर्थक मिल गए.

लेकिन मुख्यग्रंथियों के सामने झुकने के बावजूद बरनाला ने अपना नरमपंथी रवैया नहीं छोड़ा है. दरअसल वे समान विचारधारा वाले नेताओं से यह कहते रहे हैं कि राष्ट्रविरोधी तत्व उन सबको नष्ट कर दें, इसके पहले ही उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए. अमरिंदर सिंह इस अभियान में सहर्ष शामिल हुए हैं.

नई रणनीति की सफलता के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी. बादल, गुरचरण सिंह तोहड़ा और जसबीर सिंह रोड़े सरीखे कई अकाली नेता जेल में हैं उनकी रिहाई से स्थिति में भारी बदलाव आ सकता है. आतंकवादी हत्याओं में वृद्धि हो सकती है या केंद्र की पंजाब नीति में बड़ा परिवर्तन हो सकता है. लेकिन बरनाला के लिए दिलासे की एक बात तो है ही. उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है.

—विपुल मुद्गल, अमृतसर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

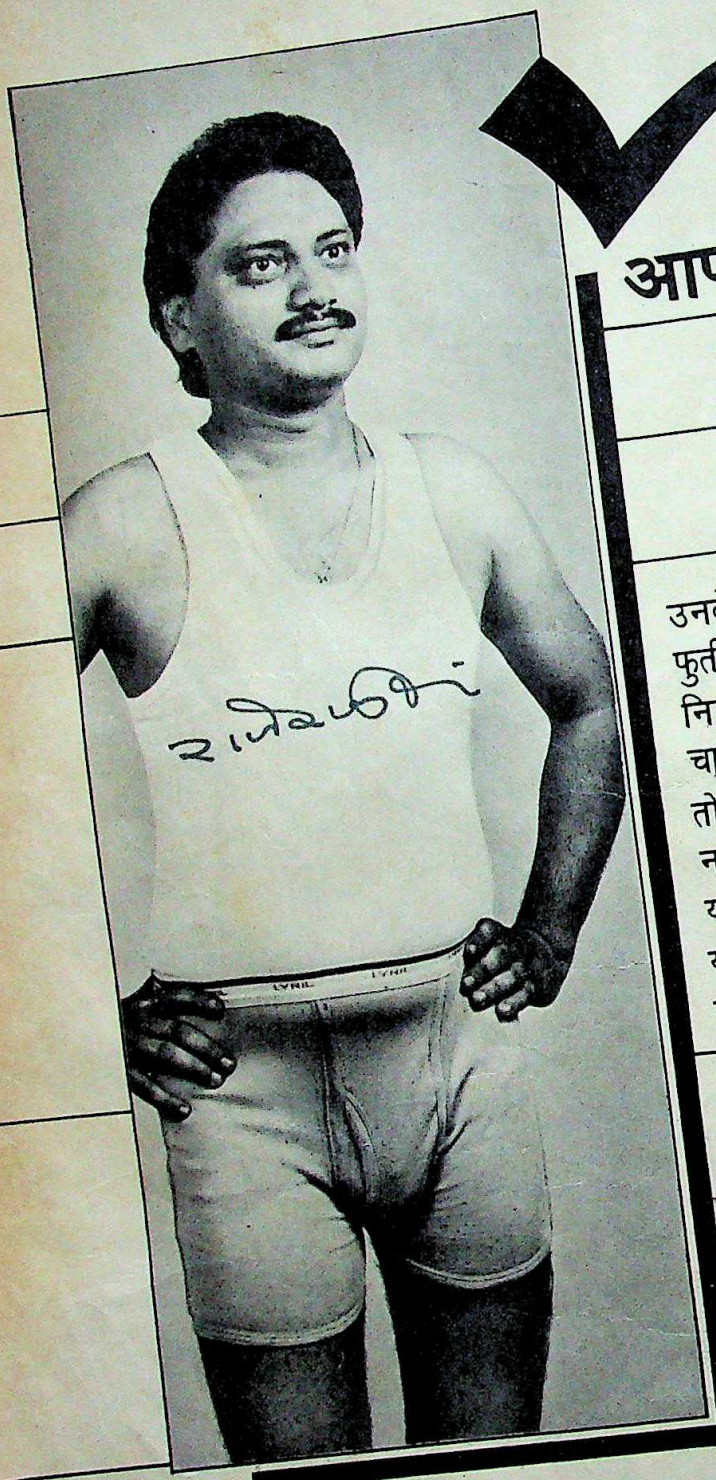

आप जैसे जवां मर्द के लिये

उनके लिए जो तेज तर्रार हैं
फुर्तीले हैं प्रगतिशील है.....
निरंतर समय के साथ-साथ चलना
चाहते हैं हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हैं
तो लीजिए – लिरिल की सौगात
नयी पीढ़ी की नयी पसंद
यह खूबसूरत है.....
यह मजबूत है यह टिकाऊ है
यह कई रंगों में मिलती है

लिरिल

- अंडरवियर
- बनियान

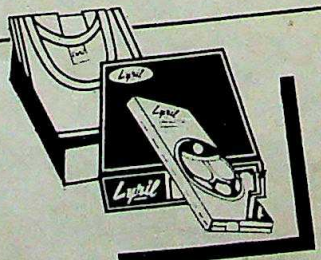

Lyril®

चुस्त फुर्तीले मर्दों
की पहली पसंद

ATUL PUBLICITY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नज़रे-इनायत को बेताब

विश्वनाथ प्रताप सिंह की बगावत इंका के राजपूतों के लिए मुसीबत बन गई है. कइयों को लगता है कि उन पर वी.पी. सिंह से सहानुभूति रखने का संदेह किया जा रहा है.

अपने को उपेक्षित महसूस किए जाने वाले लोगों में बिहार से लोकसभा सदस्य सत्येंद्र नारायण सिन्हा के समर्थक भी हैं. सिन्हा 1984 में इंदिरा गांधी की पहल पर अपने 5,000 समर्थकों के साथ इंका में लौटे थे. पिछले पखवाड़े सिन्हा और उनकी पत्नी

कृष्ण मुरारी किशन

अपने समर्थकों के साथ सिन्हा (मध्य में): उपेक्षा का एहसास

किशोरी (जो खुद भी सांसद हैं) ने पटना में अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई तो उन्हें शुभकामनाएं देने राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह, मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी पहुंचे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इसका मकसद आलाकमान को यह जताना भी था कि राजपूतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता. राज्य के राजपूत केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ अपनी जाति के प्रतिनिधित्व को लेकर ही नहीं बल्कि राज्यसभा चुनाव के लिए हुए टिकटों के वितरण को लेकर भी नाखुश हैं.

पिछले महीने सिन्हा ने किसान मजदूर समन्वय समिति के झंडे तले अपने समर्थकों की एक बैठक आयोजित की. इसका मकसद जमींदारों और भूमिहीनों के बीच सद्भावना पैदा करना था. कई लोगों को लगता है कि सारी कसरत पार्टी में अहमियत पाने के लिए है. गरीबों और अल्पसंख्यकों में इंका का आधार पहले ही खत्म हो रहा है. बस, अब राजपूतों के विद्रोह की कसर बाकी है.

जीतते हैं तो शान से

मणिपुर के मुख्यमंत्री आर.के. जयचंद्र सिंह ने आखिर सफलता पा ही ली. उन्होंने चुनाव लड़ा और विजयी हुए. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मार्च में जब रिशांग कीसिंग को हटाकर उनकी जगह जयचंद्र सिंह को बैठाने का फैसला किया था तो पार्टी के भीतर नए मुख्यमंत्री के विरोधी कहने लगे कि इस नेता ने तो अभी तक तो कोई चुनाव ही नहीं जीता है.

जयचंद्र सिंह

खैर, जयचंद्र सिंह ने सागोलबांद निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा और इतने भारी मतों से जीते कि उनके विरोधी भी दंग रह गए. उनकी झोली में 11,939 वोट पड़े जबकि प्रतिद्वंद्वी विपक्षी उम्मीदवार एम. सिंह को सिर्फ 2,080 वोट मिले. विपक्षी मणिपुर पीपुल्स पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के पास गई और आरोप लगाया कि जयचंद्र सिंह ने धांधली करके चुनाव जीता. अपनी जीत से प्रसन्न मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि यदि कोई साबित कर दे कि धांधली हुई है तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे.

सड़क पर उतरी सरकार

दिल्ली में स्थानीय इंका और प्रशासन की खस्ता हालत के कारण अति सक्रिय उपराज्यपाल हरकिशनलाल कपूर को खुद ही मोर्चे पर उतर आना पड़ा है. पिछले पखवाड़े वे अपनी मर्सिडीज बेंज में ट्रक ड्राइवरों का पीछा कर रहे थे और तेज रफ्तार से ट्रक चलाने तथा ज्यादा बोझ लादने के जुर्म में उन्हें पर्चियां थमा रहे थे. वे नियम तोड़ने वाले ट्रकों के सामने अपनी कार खड़ी करते और अपने कार टेलीफोन से ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाते देखे गए.

लेकिन पुलिस वाले इससे खुश नहीं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम तो चुनावी दौरों के समय ही राजनीतिकों के साथ रहते हैं. लेकिन अब जबकि राजनीतिक शांत हैं, कपूर सिरदर्द बने हुए हैं." इंका नेता भी कपूर की इस सक्रियता को अपने क्षेत्र में दखलंदाजी मानते हैं. इन नेताओं ने कुछ समय पहले उनसे कहा भी था कि वे ज्यादा सक्रियता न दिखाएं. लेकिन नगर निगम के चुनाव पास होने के कारण वे फिर सक्रिय हो गए ताकि लोगों को लगे कि दिल्ली में सरकार नाम की भी कोई चीज है.

एक और सेना हरियाणा में

हाल ही में इलाहाबाद अभियान में अपनी 'हरी सेना' को मिले प्रचार से प्रोत्साहित होकर देवीलाल के नेतृत्व वाला हरियाणा लोकदल अब 'बेरोजगार सेना' बना रहा है. मुख्यमंत्री के प्रिय पात्र विधायक रघु यादव ने इस 'सेना में लाखों बेरोजगार युवकों' को भर्ती करने के लिए पिछले महीने विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों का दौरा शुरू कर दिया. यादव का दावा है कि असम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस सेना को भारी

हरियाणा की 'बेरोजगार सेना': नया जोश

समर्थन मिला है. इसके पीछे आयोजकों का मकसद है लाखों बेरोजगार युवकों का दिल्ली मार्च और काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करवाना. यादव का दावा है कि उनका यह अभियान बेहद लोकप्रिय साबित हो रहा है और अब तक 50,000 से अधिक युवक सेना में शामिल हो चुके हैं.

लोकदल के दर्शन के मुताबिक, सिर्फ उत्पादन बढ़ाकर देश के 2.1 करोड़ पंजीकृत बेरोजगारों के लिए काम पैदा नहीं किया जा सकता. सेना के संयोजक ने कहा, "रोजगार बढ़ाने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों में काम के ज्यादा अवसर पैदा करने होंगे."

इस अभियान से देश की आर्थिक योजना बदले या न बदले, और बेरोजगारों को मदद मिले या न मिले, देवीलाल को ज्यादा प्रचार पाने में मदद जरूर मिलेगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुमायूं खां

'पड़ोसी की इज्जत अपनी इज्जत है'

भारत में पाकिस्तान के राजदूत का काम कोई हंसी-खेल नहीं. लेकिन भारत में चार वर्षों तक पाकिस्तानी राजदूत रहे हुमायूं खां ने अपने कार्यकाल में आई मुसीबतों का सामना बेहद कुशलता से किया. उनकी कूटनयिक प्रतिभा को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान का विदेश सचिव मुकर्रर किया गया है. इस्लामाबाद लौटने से पहले खां ने विशेष संवाददाता ***रमिंदर सिंह*** *से बातचीत की. कुछ अंश:*

● भारत-पाक रिश्ते दोनों देशों की अंदरूनी और राजनैतिक मजबूरियों का सबसे पहले शिकार होते हैं, इसके मद्देनजर क्या रिश्तों में सुधार हो सकता है?

हमारा पहला काम लोगों के दिमाग से यह बात निकालना है कि पाक मुखालफ कोई भी बात भारत में और भारत मुखालफ कोई भी बात पाकिस्तान में मकबूल हो सकती है. ये चीजें पुरानी पड़ गई हैं.

प्रमोद पुष्करणा

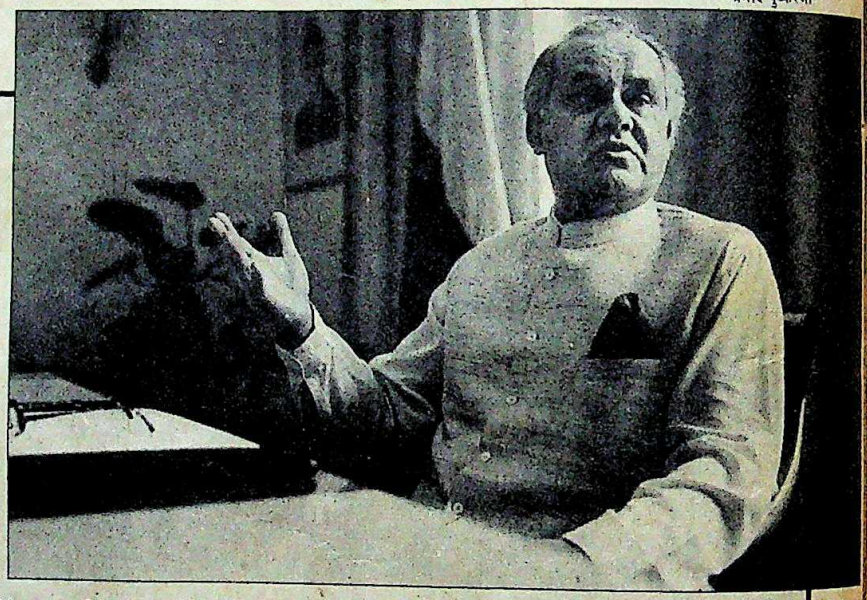

● अब आप बतौर विदेश सचिव नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं. भारत-पाक रिश्ते बेहतर बनाने में आप अपने योगदान को कैसे आंकते हैं?

दोतरफा रिश्तों की बेहतरी में किसी बड़ी कामयाबी का दावा करना मेरे लिए वाजिब नहीं. आप इसे नाकामी कबूल करना कह सकते हैं लेकिन हमारे निशाने इतने ऊंचे होते हैं कि किसी भी राजदूत को कभी तसल्ली नहीं हो सकती. इसके अलावा यह मुश्किलों का दौर था. फिर भी हम भारत-पाक रिश्तों को खुशगवार बनाए रखने में कामयाब रहे. जाहिर है दोनों मुल्कों को इस बात का एहसास है कि तनातनी की इंतिहा नुकसानदेह है.

"दोनों मुल्कों के लोगों में दोस्ती की ख्वाहिश हमारा सबसे बड़ा सरमाया है. अवामी राय को असरअंदाज करने वाले लोगों को चाहिए कि इसे फिजूल न गंवाएं क्योंकि इससे नुकसान मुस्तकिल हो सकता है"

● क्या तनातनी भारत-पाक रिश्तों में अब आम बात हो गई है?

मैं नाउम्मीद नहीं हूं. फिलहाल जो मुश्किलें हैं वे मुस्तकिल नहीं हैं. वे किन्हीं खास हालात की पैदावार हैं. तनाव की वजहें साफ जाहिर हैं. कुछ तो नजरियाती हैं और कुछ तवारीख की पैदावार. कई तो हमेशा से चली आई हैं, जैसे दोनों मुल्कों की तरफ से हथियारों की खरीद, एटम बम का मसला, दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते वगैरह. ये मसले तनाव की जड़ भी हैं और उसकी निशानियां भी. बदकिस्मती से दोनों मुल्कों में ऐसे रुझान हैं जिनके चलते रिश्तों में बेहतरी के लिए पहले दीगर कदम उठाने की शर्तें रखी जाती हैं. मेरे जमाने में खामखाह के कुछ दुराव मिटाने की कोशिशें हुईं. जैसे 1985 में सदर जिया उल हक और आपके वजीरे आजम राजीव गांधी की मुलाकात. यह कोशिश सिरे चाहे न चढ़ सकी पर मैं इसे ही सबसे बढ़िया तरीका मानता हूं.

● आपके विदेश सचिव बनने से दोनों मुल्कों के रिश्ते बढ़िया मुकाम पर पहुंचेंगे क्या भारत ऐसी उम्मीद रख सकता है?

मैं बढ़ा-चढ़ाकर कुछ नहीं कहना चाहता. आखिर मैं एक सरकारी अफसर हूं. फिर भी भारत से रिश्ते सुधारने के लिए मैं अपनी सरकार की नीतियों को अमल में लाने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा. दोनों मुल्कों के लोग सचमुच अमन-चैन चाहते हैं. मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों मुल्कों के रहनुमा महसूस करेंगे कि वे दूसरे मुल्क की तारीफ करके सियासी फायदे में रह सकते हैं. यह ख्वाब तो लगता है लेकिन पहले के रवैये के मुकाबले हकीकत के ज्यादा करीब है.

● क्या आप कहना चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के नेता हकीकत से वाकिफ नहीं?

लोग क्या सोचते हैं इसका पता तो अखबारों, रेडियो वगैरह से चलता है. लेकिन अपने तजुर्बे से मैंने देखा कि भारत के लोगों की राय अमूमन यहां के अखबारों से मेल नहीं खाती दोनों मुल्कों के लोगों में दोस्ती की ख्वाहिश हमारा सबसे बड़ा सरमाया है. अवामी राय को असरअंदाज करने वाले लोगों को चाहिए कि वे इस सरमाये को फिजूल में न गंवाएं क्योंकि इससे नुकसान मुस्तकिल हो सकता है और हमारे रिश्तों की बुनियाद तक हिल सकती है.

● अगर रिश्तों में सुधार लाने के लिए उन कामों की फेहरिस्त बनानी हो जिन्हें आप तरजीह देंगे, उसका कोई खाका बताएंगे?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस बारे में दो नजरिये हैं. पाकिस्तान अपनी हिफाजत को ज्यादा अहमियत देता है जबकि भारत संस्कृति, व्यापार और आवाजाही को. दोनों नजरिये एक-दूसरे को मजबूत बनाने वाले हैं. लेकिन सियासी और फौजी मामलों में बड़ा हिस्सेदार होने के नाते भारत पाकिस्तान के अंदेशों को दूर करने में ज्यादा असरदार कदम उठा सकता है.

● ***किस तरह के कदम?***

मसलन व्यापक सुरक्षा संधि जिस पर अभी विचार हो रहा है. इसके तहत दोनों एक-दूसरे के खिलाफ जंग न छेड़ने का हलफ लेंगे. लेकिन इसमें कोई शर्त क्यों लगाई जाए? हम एक-दूसरे से इसका वायदा करें. शर्तें लगाए जाने से छोटे देशों में शक पैदा होता है. लड़ाई न करने का करार इस सिलसिले में एक बड़ा कदम होगा. इसी तरह हम एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का समझौता भी कर सकते हैं. फिलहाल जुबानी करार है और मुझे यकीन है कि हम और भारत इसका ईमानदारी से पालन करेंगे. मुझे समझ नहीं आता एटमी करार का पंजाब के हालात से क्या ताल्लुक है?

● ***पाकिस्तान अपनी तरफ से क्या कदम उठाना चाहता है?***

बेहतर है नई पहल बड़े हिस्सेदार की तरफ से ही हो. मेरा ख्याल है कि भारत-पाक रिश्ते इसी सतह पर रखने के लिए आपसी भरोसे की सख्त जरूरत है. और फिर, पता नहीं भारत पाकिस्तान के बारे में कोई बात तीसरे मुल्क को बताना क्यों जरूरी समझता है. दुनिया के इस हिस्से में तो अपने पड़ोसी की इज्जत ही अपनी इज्जत समझी जाती है. पड़ोसी को दुनिया की नजरों में गिराकर कुछ हासिल नहीं होता.

प्रभात पंजियार

"सरहद पर चल रही गैरकानूनी सरगर्मियों को हम रोकना चाहते हैं. आप पाकिस्तान की हिफाजती एजेंसियों पर गैरकानूनी घुसपैठ रोक पाने में नाकामी का इलजाम तो लगा सकते हैं, पर इसे बदनीयती नहीं समझा जाना चाहिए"

● ***कश्मीर का मसला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना क्या इसी श्रेणी में नहीं आता?***

शिमला समझौते के मुताबिक हमें कश्मीर का झगड़ा अमन चैन से निबटाना है. दोनों मुल्क अपने-अपने दावों पर कायम हैं. अपनी इसी राय को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाहिर करने का मतलब मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाना नहीं है.

● ***पाकिस्तान के विदेश सचिव के नाते क्या आप दोतरफा रिश्तों के मामलों को नई शक्ल देंगे?***

हमारे पास पहले ही इसका अच्छा मसौदा है. इसमें सभी खास मुद्दे शामिल हैं. इसमें फेरबदल के बारे में इतना ही कहूंगा कि हम मामूली वाकयात के कारण इसे बदलने पर जोर न दें.

● ***पर पंजाब का मामला क्या छोटी बात है?***

पिछले चार साल से पंजाब का मसला हमारे रिश्तों को कसैला बनाए हुए है. हमने भारत को समझाने की कोशिश की कि अपनी सरहद पर गड़बड़ी को हम अपनी हिफाजत के लिए मुफीद नहीं मानते पर उसने अनसुनी कर दी. इसकी वजह नजरिये में फर्क और जानकारी की कमी होना भी है.

● ***पर आतंकवादी कबूल करते हैं कि वे पाकिस्तान आते-जाते रहे हैं.***

हमने कब कहा कि सरहद पर गैरकानूनी सरगर्मियां नहीं चलतीं. हम इन्हें रोकना चाहते हैं. लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की हमारी कोई मंशा नहीं है. सरहद पर तैनात लोगों के नाकारापन की वजह से इनके अमल में कुछ खामियां हो सकती हैं. आप पाकिस्तान की हिफाजती एजेंसियों पर गैरकानूनी घुसपैठ रोक पाने में नाकामी का इलजाम तो लगा सकते हैं मगर इसे बदनीयती नहीं समझा जाना चाहिए.

प्रमोद पुष्करणा

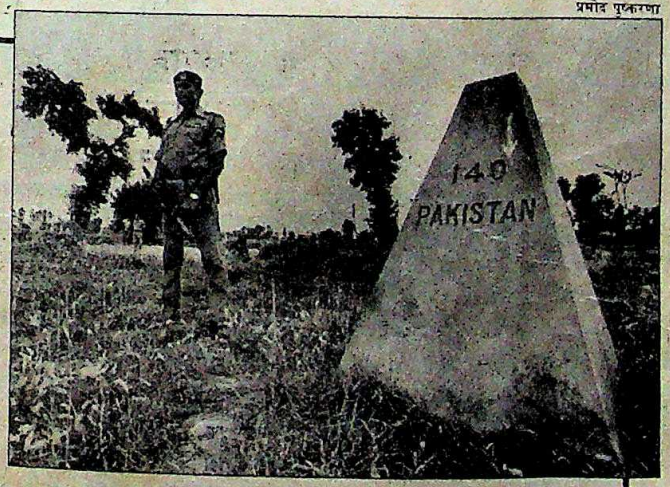

"मेरे जमाने में आपसी दुराव मिटाने की कुछ कोशिशें हुईं जैसे सदर जिया उल हक और आपके वजीरे आजम राजीव गांधी की मुलाकात. यह कोशिश सिरे चाहे न चढ़ सकी पर मैं इसे ही सबसे बढ़िया तरीका मानता हूं"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सैबाल दास

ज्योति बसु

'प्रश्न जन समर्थक नीतियों का है'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु कुछ हफ्तों बेहद व्यस्त रहे. पिछले ही हफ्ते 75वें साल में पहुंचे बसु अभी हाल में पेइचिंग के दौरे से लौटे थे. वे अपने राज्य में गोरखालैंड आंदोलन की ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए हुई वार्ताओं में भी शामिल रहे हैं. पिछले पखवाड़े उन्होंने इन सभी मुद्दों समेत रूस में हो रही महत्वपूर्ण तब्दीलियों के बारे में वरिष्ठ संवाददाता ***कमलजीत रतन*** *से विस्तार से बातचीत की. कुछ अंश:*

● ***राष्ट्रीय दृष्टिकोण से दार्जिलिंग समस्या कितनी गंभीर है?***

हमने इसे हमेशा राष्ट्रीय समस्या समझा है क्योंकि यहां उठे प्रतिगामी कदम का असर हर कहीं होगा. केंद्र सरकार ऐसी ताकतों के आगे अक्सर झुकती रही है और खामियाजा हमें भुगतना पड़ा. इसलिए हमने शुरू में ही गोरखालैंड आंदोलन को राष्ट्र विरोधी करार दिया क्योंकि उसकी मांग भारत से अलग राज्य कायम करने की रही है. बाद में घीसिंग ने अपनी गलती महसूस करके पश्चाताप किया और भारत के भीतर ही अलग राज्य की मांग रखी.

● ***इस समस्या में केंद्र की भूमिका के बारे में आपकी क्या राय है?***

सच पूछिए तो मैं प्रधानमंत्री के बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता. पता नहीं इन बयानों से क्या नुकसान हुआ पर उनसे दार्जिलिंग के उग्रवादियों को शह जरूर मिलती है. जब कोई ठोस समझौता हुआ ही नहीं तो राज्य सरकार पर समझौता भंग करने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? पता नहीं प्रधानमंत्री ने ये बयान कैसे दिए और उन्हें कौन, कैसी सलाह देता है.

● ***हाल की तितरफा बैठकें किसी योजना के तहत हुईं या संयोग से?***

ये नियोजित ही थीं. बूटा सिंह ने मुझे बुलावा भेजा. मैं घीसिंग से इस शर्त पर मिलने के लिए तैयार था कि वे गोरखालैंड की चर्चा न छेड़कर बातचीत को पर्वतीय विकास परिषद के मुद्दे तक सीमित रखें. बूटा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिंह ने मुझे इसका आश्वासन दिया. मैंने घीसिंग और उनके साथियों से कहा कि वे यह रवैया छोड़कर पहले तय हुए सारे फैसले मान लें ताकि बातचीत जारी रह सके.

● ***घीसिंग से आपके किस तरह के संबंध हैं? एक बार उन्होंने आपको बुद्धिमान मुख्यमंत्री भी तो कहा था.***

उनसे बातचीत करने तक तो ठीक है. मैंने उनसे कहा कि आओ हम दोस्ती कर लें. आखिर हम भी तो पिछले 20 वर्षों से स्वायत्तता और नेपाली भाषा को मान्यता दिलाने की बात करते आ रहे हैं. फिर मैंने उनसे पूछा कि आप गोरखालैंड की मांग क्यों उठा रहे हैं, नेपालियों के लिए तो हमने आपसे ज्यादा काम किया है.

● ***क्या आपको लगता है कि घीसिंग के साथ हर समझौता नाकाम रहेगा?***

अव्वल तो मैं घीसिंग को पर्वतीय इलाकों का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं मान सकता, दूसरी पार्टियां भी तो वहां हैं.

● ***अभी आप चीन गए थे. सीमा समस्या पर चीनियों का क्या रुख है?***

वे मैकमोहन रेखा को नहीं मानते पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. हम दो बड़े देश हैं और किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं. चीनियों का मानना है कि यह समस्या तो किसी दिन सुलझ जाएगी. पर वे दूसरे मामलों में संबंध सुधारने के इच्छुक हैं.

● ***अगर कुछ लेने-देने से मामला सुलटा तो आपकी पार्टी का क्या रुख होगा, खासकर इस संदर्भ में कि 1962 में आपकी पार्टी मैकमोहन रेखा को संदेह की नजर से देखती थी? बढ़िया एकमुश्त समझौता क्या हो?***

मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा. दोनों सरकारों में बातचीत होने दीजिए. मेरे कुछ कहने से समस्या पैदा हो सकती है.

● ***पेइचिंग में आपको कैसे मिजाज दिखाई दिए? और फिर विदेश मंत्रालय के मिजाज का भी कोई अंदाज बताइए?***

दोनों सरकारें संबंध सुधारने की इच्छुक हैं. चीनी नेताओं ने मुझसे पूछा कि क्या राजीव गांधी इस मामले में ईमानदारी बरत रहे हैं. मेरा जवाब था; हां. मैंने उन्हें बताया कि बहुत से मामलों में भारत सरकार से हमारा मतभेद है मगर इस मुद्दे पर हम एक हैं. वे भी समाधान ही चाहते हैं. लेकिन, जैसा कि आपने कहा, कुछ लेना-देना तो होगा ही इसलिए मैं कह नहीं सकता वह किस हद तक होगा. यह तो बातचीत से ही तय होगा.

● ***क्या आप भारत-चीन समझौता होने की प्रक्रिया में किसी तरह मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहेंगे?***

नहीं, मैं मध्यस्थ कैसे हो सकता हूं? मैं केंद्र सरकार में नहीं हूं. मैं चूंकि चीन जा रहा था इसलिए राजीव गांधी चाहते थे कि मुझे भारत सरकार की स्थिति की जानकारी हो. वहां से लौटने पर मैंने उन्हें चीनी नेताओं की प्रतिक्रिया भी बताई.

● ***रूस में व्यापक बदलाव हो रहे हैं. माकपा का इस बारे में क्या नजरिया है?***

इन व्यापक बदलावों का अभी हमें जायजा लेना है. हमें उनके दस्तावेजों का अध्ययन करना है. वे अब समाजवाद और मंडी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं. रूसी अभी भी अपने को समाजवादी देश कहते हैं और हर क्षेत्र में अपना पुख्ता नियंत्रण बताते हैं. लेकिन फिर कुछ क्षेत्रों में काम नहीं हुआ जिससे खुलेपन और पुनर्निर्माण की ये सब बातें शुरू हुईं. अगर कोई अच्छी बात होती भी है तो उससे दुनिया भर के समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन को बल ही मिलेगा.

● ***रूसी तो आत्मालोचना करने के साथ-साथ व्यक्ति पूजा को भी बढ़ावा दे रहे हैं. हमारे यहां भी ज्योति बसु का जलवा बढ़ा है. आम तौर पर माना जाने लगा है कि 'बसु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता.'***

> **"राजीव गांधी का राष्ट्रीय विकल्प पैदा करना ही होगा. विकल्प का मतलब राजीव गांधी को हटाना ही नहीं है. हमें जन समर्थक कार्यक्रम और नीतियां आगे लानी होंगी"**

खुद गोर्बाचेव ने व्यक्ति पूजा की निंदा की है. मगर मार्क्सवादी होने के नाते हम जानते हैं कि व्यक्तियों की भूमिका होती है. व्यक्ति पूजा से पार्टी को नुकसान पहुंचता है. मेरे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वह अखबारों की उपज है. हमारी पार्टी में व्यक्ति पूजा की कोई जगह नहीं है. हमारा कामकाज सामूहिक तौर पर होता है. कई बार मैं सुनता हूं 'ज्योति बसु के बाद कौन', 'ज्योति बसु के बाद क्या होगा'. मैं यह सब कुछ नहीं मनाता.

● ***आपकी पार्टी में क्या पर्याप्त लोकतंत्र है? बरखास्तगी के मामले क्यों बढ़ गए हैं?***

निश्चय ही पार्टी में पर्याप्त लोकतंत्र है. पर हमारा नियम है कि जब एक दफा फैसला हो जाए तो हर किसी को वह मानना पड़ेगा. उसके बाद किसी को आलोचना करने का अधिकार नहीं. अगर कोई ऐसा करता है तो पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं बचती.

● ***हाल ही में फारवर्ड ब्लॉक और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने आपके नेतृत्व पर उंगली उठाई है.***

आपको पता होना चाहिए, हमारी मिली-जुली सरकार है. उन्होंने मेरी आलोचना इसलिए की क्योंकि मैंने कहा था कि वे पंचायत सीटों के बंटवारे पर वाम मोर्चा के बीच हुए समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं. वे गलती पर थे. माकपा का नेता होने के नाते मुझे अपनी पार्टी की तरफदारी करनी थी.

● ***वी.पी. सिंह के साथ आपकी पार्टी का क्या समझौता है?***

चुनाव जीतने के बाद हमने उन्हें अपने दफ्तर बुलाकर पूछा कि वे कौन-से मुद्दे उठा रहे हैं, मसलन मजदूरों और किसानों के लिए उनके पास क्या नीतियां हैं. हम मुद्दों पर उन्हें समर्थन देंगे और राजीव गांधी की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे.

● ***पर इन खबरों में क्या कोई सचाई है कि माकपा वी.पी. सिंह के इर्दगिर्द जुटी ताकतों के साथ चुनावी गठजोड़ करने जा रही है? अगर नहीं तो ऐसे गठजोड़ में वामपंथियों की क्या भूमिका होगी?***

वी.पी. सिंह अगर सांप्रदायिक पार्टियों से दूर रहते हैं तो उनसे गठजोड़ की संभावना भी हो सकती है. हम राजीव गांधी की जगह इन ताकतों को सत्ता पर नहीं बिठाना चाहते. हम वैयक्तिक तौर पर राजीव गांधी के खिलाफ नहीं हैं. हमें उनकी नीतियों से विरोध है. वरना हम अपने कार्यक्रम ही जारी रखेंगे और मुद्देवार फैसले लेंगे.

● ***इंका का राष्ट्रीय विकल्प क्या हो सकता है? क्या केंद्र में जनता पार्टी जैसी कोई सरकार बनने की संभावना है जिसके नेता वी.पी. सिंह होंगे?***

राजीव गांधी का विकल्प पैदा करना ही होगा. यहां कोई चाहे राजनीति में हो या नहीं, देश में रहता हो या नहीं, नेता बन सकता है. आखिर 70 करोड़ लोग हैं. विकल्प राजीव को हटाना भर नहीं है. हमें जन समर्थक कार्यक्रम और नीतियां आगे लानी होंगी.

● ***वी.पी. सिंह को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है.***

यह हम नहीं कर रहे. हमने तो उनसे अगले कुछ महीनों में अपने कार्यक्रम और नीतियों की जानकारी देने को कहा है.

● ***आखिरी सवाल. 75 साल की उम्र में भी आपमें इतनी स्फूर्ति कैसे है?***

मैं एक उद्देश्य के प्रति समर्पित हूं और वह है दुनिया को बदलना.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एड्स

दहशत की दस्तक

पश्चिमी देशों की भयानक बीमारी के भारत में भी लक्षण

सच्चे प्रेम और एड्स में क्या फर्क है?

प्रेम भले स्थायी न हो, एड्स स्थायी होता है.

यह मजाक अब मजाक नहीं रह गया. कोई भी अब इसे हंसकर नहीं टालता. एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडिफीसिएंसी सिड्रोम) को अब तक तो पश्चिमी मुल्कों का रोग या दूसरों का सरदर्द कहकर टाल दिया जाता था. समझा जाता था कि भारत की सामाजिक और आनुवंशिक परिस्थितियों के चलते यह घातक रोग भारत से दूर ही रहेगा. पर अनुसंधानों ने साबित कर दिया है कि भारत में भी एड्स का प्रवेश हो सकता है. आज इस भयानक रोग ने कितना तहलका मचा रखा है इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ संवाददाताओं ***सिमरन भार्गव*** *और* ***डेविड देवदास*** *द्वारा:*

पिछले महीने बंबई की कुख्यात शुक्ला जी स्ट्रीट से एक 38 वर्षीया बीमार वेश्या जे.जे. अस्पताल में आई. वह पेचिश, वजन में भारी कमी, तेज बुखार से पीड़ित थी. लगातार योनि-स्राव की शिकायत भी उसे थी. अस्पताल आने के पहले तक वह कई डॉक्टरों से इलाज पर करीब 30,000 रुपए खर्च कर चुकी थी. जे.जे. अस्पताल के डॉक्टरों ने आखिरी फैसला सुनाया कि वह एड्स से पीड़ित है. यह सजा-ए-मौत के फैसले जैसा ही है. चौदह दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसकी शव परीक्षा करने के लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं था.

लगभग इसी दौरान दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स का पहला मरीज दाखिल हुआ. यह 55 वर्षीय मरीज मेकेनिकल इंजीनियर है और पहले अफ्रीका में रहता था. वह अपनी पत्नी के साथ पहियेदार कुर्सी पर अस्पताल में आया. बाद में पाया गया कि उसकी पत्नी में भी एड्स के विषाणु (वाइरस) मौजूद हैं. लगभग महीने भर वह संस्थान के एक अंधेरे छोटे कमरे में पड़ा रहा. अब तक रोग ने उसे इतना जकड़ लिया था कि जुकाम भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकता था. देखरेख कर रहे डॉक्टर ए.एन. मालवीय से उसने कहा, "आप मेरे लिए भगवान के समान हैं. कृपया मुझे दुनिया भर में मजाक का पात्र नहीं बनने दीजिएगा." पिछले हफ्ते अस्पताल से उसकी छुट्टी कर दी गई.

इस तरह भारत में एड्स एकाएक सुर्खियों में आ गया. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. अवतार सिंह पेंटल ने कहा, "पिछले महीने मैंने कहा होता कि यह रोग मद्रास तक ही सीमित है. पर अब मैं ऐसा नहीं कह सकता. हां, मद्रास में इसकी निगरानी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध है."

फरवरी में जालंधर में एक वयोवृद्ध पति-

यूरोप और अमेरिका में तो इस रोग का खौफ घर कर गया है लेकिन फिलहाल भारत में उतनी दहशत नहीं है

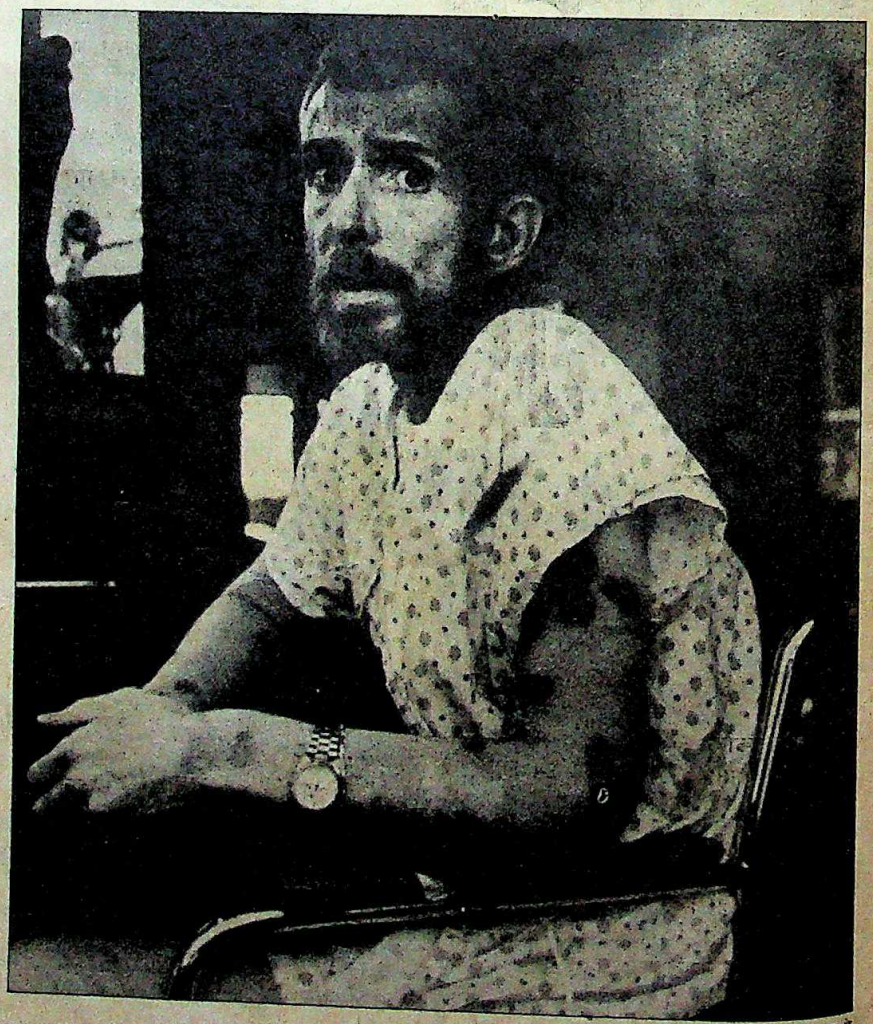

एड्स का एक यूरोपीय मरीज

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजन्य से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पत्नी की मृत्यु हो गई, चंडीगढ़ में एक वृद्ध विधुर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उधर त्रिवेंद्रम में भी एड्स के विषाणु पाए गए हैं. कर्नाटक में पिछले हफ्ते बेलगांव की एक देवदासी में यह रोग पाए जाने के बाद सावधानी बरती जाने लगी. देवदासी को यह

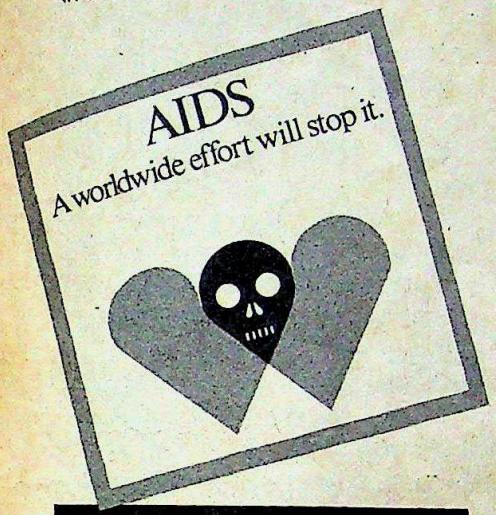

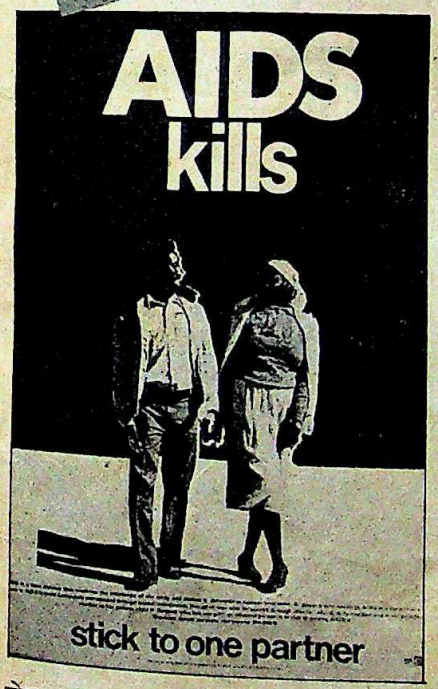

रोग एक ग्राहक से लगा था. उसके नवजात शिशु में भी एड्स के लक्षण पाए गए. अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस भयावह रोग से पीड़ित 332 लोगों में से 24 की मौत हो चुकी है.

यूरोप और अमेरिका में तो इस रोग का भयानक खौफ घर कर गया है पर भारत में अभी ऐसा नहीं है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ. एन.के. शाह ने कहा, "विदेशी पत्रिकाएं 'टाइम्स' और 'न्यूजवीक' पढ़ने वाले लोग ही इस रोग के बारे में जानते हैं. जिन्हें इसकी

अवतार सिंह पेंटल

'संयम बरतना बहुत जरूरी'

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक अवतार सिंह पेंटल पिछले महीने अपने बेतुके बयान "विदेशियों और आप्रवासी भारतीयों के साथ संभोग पर पाबंदी लगनी चाहिए" की वजह से पूरे देश में चर्चित हो गए थे. पिछले हफ्ते वरिष्ठ संवाददाताओं ***सिमरन भार्गव*** *और* ***डेविड देवदास*** *ने उनसे बातचीत की. बातचीत के अंश:*

● ***आपने ऐसा बेतुका बयान क्यों दिया?***

मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इससे एक करोड़ लोग जागरूक हो गए. इसका मकसद बहस की शुरुआत करना है.

● ***क्या आपको लगता है कि यौन गतिविधियों की रोकथाम हो सकती है?***

यह हरेक के बेडरूम में निगाह रखने का सवाल नहीं है. आपको ऐसे शख्स के साथ संभोग करने का हक नहीं है जिससे पूरा देश ही तबाह हो जाए. भारत के लोग कानून की भाषा ही समझते हैं.

● ***आपके बयान का आधार क्या था?***

अमूमन 25 से 45 वर्षीय महिलाओं से मिली जानकारी. यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि हालात अब उतने ठीक-ठाक नहीं रह गए हैं.

● ***हालात किन वजहों से बदले हैं?***

हम मानते हैं कि हमारी महिलाएं सती साध्वी होती हैं. लेकिन महिलाओं की स्वच्छंदता के बारे में जानकर हैरान होंगे.

● ***कौन-सा तबका सबसे ज्यादा स्वच्छंद है?***

पहले बच्चे के बाद वाली महिलाएं.

● ***कॉलेज स्तर पर इस विषय पर बहस क्यों होनी चाहिए?***

राष्ट्रीय जागरूकता के लिए. कहते हैं कि कॉलेज परिसरों में यौनाचार बहुत होता है.

● ***इसके अलावा आप किस बात की सिफारिश करेंगे?***

संयम की. आदमी एक ऐसा जानवर है जो साल भर यौन क्रियाएं करता है. बाकी सारे जानवरों का वक्त तय होता है.

● ***क्या भारत को एड्स से भारी खतरा है?***

मुश्किल यह है कि यहां उतना आतंक नहीं है. आप्रवासी भारतीयों और विदेशों में रहे भारतीयों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए.

● ***विदेश जाने वाले किसी कामगार का आचरण कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?***

उन्हें ऐसा करना ही होगा. वे सुपर डीलक्स निरोध साथ ले जाएं. सुपर डीलक्स उम्दा किस्म के कंडोम हैं. वे फटते नहीं.

● ***चिकित्सक क्या कर रहे हैं?***

चिकित्सकों का कर्तव्य है कि वे ऐसे मरीजों से सहानुभूतिपूर्वक पेश आएं. हमारे लिए वे अपराधी नहीं हैं, केवल एक संख्या है—एक दुर्भाग्यपूर्ण संख्या.

● ***क्या अनुसंधान के लिए आपके पास पर्याप्त रकम है?***

हम मानते हैं कि महिलाएं सती-साध्वी होती हैं लेकिन महिलाओं की स्वच्छंदता के बारे में जानकर हैरान होंगे

पर्याप्त, हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा.

● ***क्या चुंबन से एड्स हो सकता है?***

यदि चुंबन तगड़ा हो अथवा आपके मसूड़े जख्मी हों. पखाने की खुड्डियों अथवा मच्छर काटने से एड्स नहीं होता.

● ***भारत में एड्स कितनी तेजी से फैलेगा?***

मेरे जैसे आदमियों के न होने पर बेहद तेजी से.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जानकारी की जरूरत है उन लोगों और वेश्याओं ने इसका नाम तक नहीं सुना."

मनुष्य का कई तरह के विषाणुओं से पाला पड़ा है पर एड्स का विषाणु (ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वाइरस: एचआईवी) सबसे घातक है. यह सुई की नोंक से भी करीब सोलह हजार गुना छोटा होता है. यह संभोग या नस में दी जाने वाली सुई या भ्रूण के संक्रमण से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है. पहले यह माना जाता था कि यह रोग समलैंगिकों में ही होता है क्योंकि सबसे पहले इसका पता अमेरिका के उस इलाके में लगा था जहां समलैंगिकों की बहुतायत थी. लेकिन अब माना जाने लगा है कि यह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से हो सकता

एड्स के बारे में बढ़ी चेतना के बावजूद भारत में यह बहस का मुद्दा है कि इस रोग पर कितना ध्यान दिया जाए

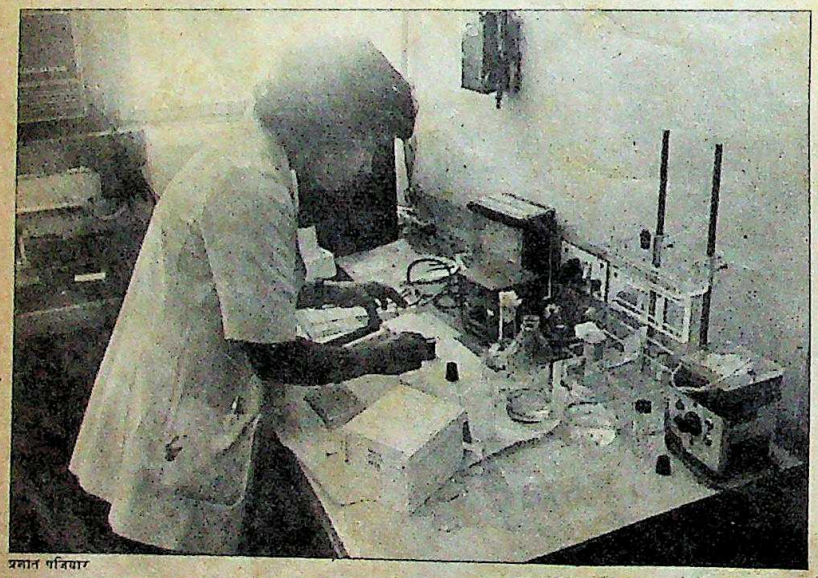

प्रभात पटियार

दिल्ली में एड्स पर चल रहा परीक्षण

है. दरअसल इस रोग के विषाणु शरीर के हर तरह के द्रव में घुलमिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं. इस रोग के बारे में सबसे खौफनाक बात तो यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति में कई साल तक इसके कोई लक्षण नहीं दिखते पर वह दूसरे व्यक्ति में इसके विषाणु फैला सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि एड्स के विषाणुओं से पीड़ितों की दुनिया भर में तादाद 50 लाख से एक करोड़ के बीच होगी. इनमें से अधिकांश को इसका एहसास तक नहीं. पांच साल पहले तक संगठन के पास इस रोग के नाम पर कोई बजट नहीं था. लेकिन पिछले साल का बजट 25 लाख डॉलर का था तो इस साल 66 लाख डॉलर का है.

भारत में अभी इसी बात पर बहस चल रही है कि इस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉ. जे.एन. पांडे ने कहा, "यह तो एक विजातीय रोग है. अपने देश में तो रैबी (कुत्ते के काटने से) से हर साल करीब 3000 लोग मर जाते हैं और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है."

सरकार ने अभी भी चेतावनी की घंटी नहीं बजाई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमारे देश में दूसरे संक्रामक रोगों की तरह एड्स कोई बड़ी समस्या नहीं है. कम-से-कम अभी तक तो नहीं ही है." एड्स की निगरानी और इसके बारे में जनशिक्षण के लिए 2.5 करोड़ रु. का बजट रखा गया है. मलेरिया के लिए 170 करोड़ रु., कोढ़ के लिए 15 करोड़ रु. और दृष्टिहीनता के लिए 7 करोड़ रु. के बजट की तुलना में यह कम ही है. गौरतलब है कि एड्स के लिए पिछले साल मात्र 50 लाख का बजट रखा गया था. फिलहाल इससे लड़ने का एक ही तरीका है कि इसके संक्रमण को रोका जाए. पिछले महीने एक बेमिसाल सुझाव डॉक्टर पेंटल की तरफ से आया, "विदेशियों और आप्रवासी भारतीयों के साथ संभोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए."

लेकिन दिल्ली की एक 28 वर्षीया महिला ने कहा, "काम वासना तो प्रकृतिजन्य इच्छा होती है. इस बुड्ढे को हमारे शयनकक्षों में ताक-झांक करने का क्या अधिकार है?" लेकिन आईसीएमआर की रणनीति सीधी-सादी है. एड्स पर शोध कर रहीं डॉ. प्रेमा रामचंद्रन कहती हैं, "और कुछ नहीं तो युवा पीढ़ी को यह जानकारी तो मिल ही जाएगी कि एड्स का संक्रमण रतिक्रिया के द्वारा ही होता है. तब वे शायद डरेंगे."

बहरहाल, आईसीएमआर ने देशभर में 42 निगरानी केंद्र खोले हैं और करीब 1.15 लाख लोगों की जांच की है. जांच के नतीजे भारत के लिए कुछ हद तक फायदेमंद दिखते हैं. इस रोग से मरने वालों में या तो आप्रवासी भारतीय हैं या वे लोग जिन्हें यह रोग विदेश में ही लगा था. देसी मामला सिर्फ तमिलनाडु में मिला है. आईसीएमआर के अनुसंधान से पता चला है कि भारत में एड्स प्राथमिक तौर पर इतर लैंगिकता से लगता है. केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को निर्देश दिया गया है कि वह देशभर में पोस्टरों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से जन-जागरण का व्यापक अभियान चलाए.

सेक्स के साथ यहां एक तरह की जो मानसिक ग्रंथी जुड़ी हुई है उसके चलते इस रोग के रोगी इलाज के लिए आगे आने में हिचक सकते हैं. पेंटल इसका समाधान सेक्स के प्रति पारंपरिक भारतीय रवैये, यहां तक कि ब्रह्मचर्य के पालन में ढूंढ़ते हैं. उन्होंने कहा, "मैं यहां की स्वच्छंदता से घबरा गया हूं. आजकल की औरतें कहीं ज्यादा आजाद हैं." रामचंद्रन ने कहा, "जो लोग स्वच्छंद सेक्स में विश्वास रखते हैं और संयम नहीं बरत सकते, उनके लिए हमारा सुझाव है कि वे कंडोम का प्रयोग करें."

आईसीएमआर के शोधार्थी एड्स को एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं. यह रोग शताब्दियों से नहीं चला आ रहा है बल्कि इसका जन्म अभी-अभी हुआ है. रामचंद्रन ने कहा, "दूसरे रोग तो 2000 वर्षों से चले आ रहे हैं और उनके कारण अनेक लोगों की मौत हो चुकी है. उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. पर एड्स का मामला एकदम उलटा है. हमें यह पता है कि हम लोगों की रतिक्रिया की प्रवृत्ति में बदलाव लाकर इसे रोक सकते हैं." इसलिए फिलहाल रणनीति यह है कि यह महामारी बन जाए इसके पहले ही हम चेत जाएं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कॉफ़ी की शान...

सर्वोत्तम 100% शुद्ध इन्स्टैंट कॉफी का शानदार स्वाद। खास चुने हुये कॉफी बीन्स से तैयार और भरपूर फ्लेवर-युक्त यह लाजवाब कॉफी आप सब का दिल जीत लेगी।
आज ही गोल्ड कैफे लाइये और अपने परिवार के साथ आनन्द लीजिए। आप स्वयं कहेंगे "वाह! कॉफी का बेमिसाल अन्दाज़!"

GOLD CAFÉ

सर्वोत्तम 100% शुद्ध कॉफी

इन्स्टैंट कॉफी

कॉफ़ी का बेमिसाल अंदाज़!

CLARION D 685/HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महिला उद्यमी

कदमों के नए निशां...

दृश्य: 1: बंगलूर में महिलाओं की एक कार्यशाला. एक सरकारी अधिकारी बड़े गर्व से चार साल पुराने कर्नाटक महिला उद्यमी संघ की अध्यक्ष और व्यवसायी मधुरा चत्रपार्थी का प्रतिनिधियों से बार-बार इन शब्दों में परिचय कराता है, "इनसे मिलिए, ये हैं मधुरा, महिला उद्यमी." शुरू में तो मधुरा कुछ नहीं कहतीं. फिर दृढ़ता लेकिन भद्रता से उस अधिकारी को झिड़कते हुए कहती हैं, "कृपया मेरा परिचय उद्यमी के रूप में कराएं. वे देख ही रहे हैं कि मैं महिला हूं."

दृश्य: 2 (पूर्व दृश्य): लगभग एक दशक पहले पारंपरिक गुजराती गृहिणी 39 वर्षीया करुणाबेन अपूर्व शाह को उनके पति गुजरात स्टील ट्यूब्स का प्रबंध निदेशक बनाकर व्यवसाय के क्षेत्र में ले आए थे. तब कंपनी का कारोबार 54 करोड़ रु. का था. करुणाबेन उन दिनों की याद करती हैं, "मैं एक गंभीर महिला उद्यमी थी. लेकिन लोग मुझे जैसे सजावट की वस्तु समझते थे." बैंक वाले महत्वपूर्ण बैठकों में उन्हें न बुलाकर उनके पति को ही बुलाते थे. लिहाजा उन्होंने अपने पति को आड़े हाथों लिया. उनसे कहा कि "यदि बैंक वाले मुझे बैठकों में आमंत्रित नहीं करेंगे तो मैं आपको भी नहीं जाने दूंगी." आज कंपनी का कारोबार 97 करोड़ रु. तक जा पहुंचा है. करुणाबेन निर्यात, उत्पादन और भर्ती का काम देखती हैं और महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने के लिए अकेले ही अहमदाबाद, दिल्ली और बंबई आती-जाती रहती हैं.

"पति का रुख अगर सहयोगी न हो तो मुश्किल हो सकती है"
साइमन टाटा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, लक्मे लि.

नामस भोजानी

"इसी मेज से हमने अपना नया जीवन शुरू किया"
तारा सिन्हा
अध्यक्ष, तारा सिन्हा एसोसिएट्स

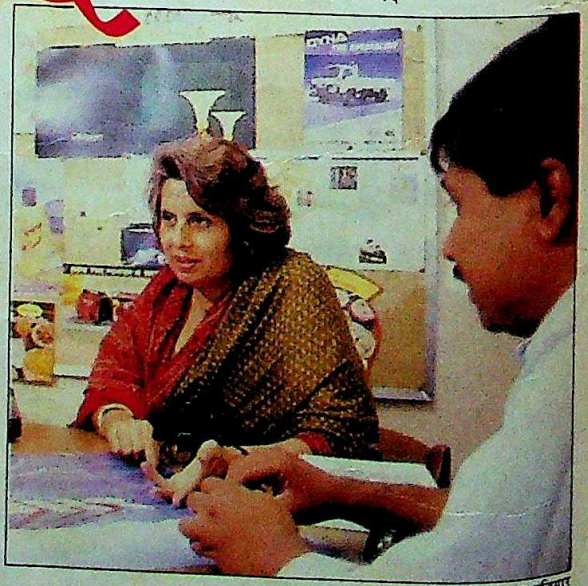

प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किरण मजूमदार

गांठ बंधी व्यवसाय से

चौंतीस बरस की किरण मजूमदार को एक दशक पहले सिर्फ अपने पिता के कारण जाना जाता था. लेकिन आज उनकी अपनी अलग शख्सियत है. किरण हमेशा से ही साहसी और स्वतंत्र विचारों की रही हैं. 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पिता के कदमों पर चलने का फैसला कर लिया. उनके पिता आर. मजूमदार भारत के पहले 'ब्रू मास्टर' (शराब बनाने वाले) हैं. इस पेशे में मुख्य तौर पर पुरुषों का ही वर्चस्व है. वे कहती हैं, "माता-पिता ने मुझे इस पेशे में जाने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की. दरअसल मां-बाप ने तो मुझे सहयोग ही दिया है."

लेकिन भारतीय समाज मददगार नहीं रहा. 22 वर्ष की उम्र में किरण आस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न विश्वविद्यालय से ब्रूइंग टेक्नालॉजी में एम.ए. करने के बाद भारत लौटीं. वे भारत की पहली 'ब्रूस्टर' (शराब तैयार करने वाली महिला) का गौरव हासिल करना चाहती थीं. लेकिन वे कहती हैं, "भारत का कोई शराब निर्माता मुझे काम पर लेने को तैयार नहीं था." वे उनसे कहते, "आप औरत हैं और यह कठिन काम है. आप मजदूरों से कैसे निबटेंगीं और वक्त-बेवक्त काम कैसे कर पाएंगी." किरण बताती हैं, "मौका देने से पहले ही उन्होंने मुझे नाकारा साबित कर दिया." कुछ समय तक उन्होंने पिता के काम में हाथ बंटाया पर निराशा बढ़ती ही गई. इसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड में असिस्टेंट ब्रू मास्टर की नौकरी के लिए आवेदन किया और नौकरी मिल भी गई. वे जाने की तैयारी कर ही रही थीं कि किस्मत ने अपना कमाल दिखाया. उनके एक मित्र ने उन्हें आयरलैंड की बायोकॉन कंपनी को माल निर्यात करने के लिए खुद कारखाना लगाने को प्रेरित किया. यह कंपनी बायो-टेक्नालॉजी के क्षेत्र में मशहूर है और विभिन्न तरह के एंजाइम बनाती है. उन्हें ब्रूइंग की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की तलाश थी. वे कहती हैं, "अपनी इकाई लगाने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था. मुझे लगा कि यह अनुभव दिलचस्प रहेगा." बायोकॉन कंपनी उनसे दो तरह के एंजाइम बनवाना चाहती थी. एक पपीते से बनने वाला 'पपैन' और दूसरा, मछली के फेफड़े से बनने वाला 'आइजिंग्लास'. आज किरण बंगलूर के बाहरी इलाके में 12 एकड़ वाले प्लॉट पर 20000 वर्गफीट में बनी आलीशान दुमंजिली इमारत में अपनी इकाई चला रही हैं. पिछले साल उनका सालाना कारोबार 3 करोड़ रु. से भी ज्यादा का रहा. 40 कर्मचारियों की सहायता से वे 20 तरह के मूलभूत एंजाइम तैयार करती हैं. उनका सालाना एंजाइम उत्पादन 120 टन है. उनके कारखाने की अनुसंधान और विकास शाखा ने दो नए एंजाइम विकसित किए हैं. किरण फिलहाल निर्यात के मकसद से इनके उत्पादन की योजना पर काम कर रही हैं. अगले साल यह परियोजना शुरू हो जाने के बाद उनका उत्पादन दस गुना बढ़ जाएगा.

शुरू में उन्हें काम करने वाले लोग ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई. लोग आते और प्रबंध निदेशक से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते. किरण कहती हैं, "जब मैं उन्हें बताती कि मैं ही प्रबंध निदेशक हूं तो उनके चेहरे लटक जाते." उन्होंने बताया कि महिलाएं तो उनके साथ काम करने में और असहज और असुरक्षित महसूस करतीं.

वे कहती हैं कि बॉस के रूप में काम करने में उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, "अक्सर औरतें सिर्फ औरत होने के नाते ही विशेष रियायतों की उम्मीद करती हैं. यह गलत है. स्त्रियों को समानता का व्यवहार करना चाहिए." उनके अनुसंधान और विकास शाखा के सर्वेसर्वा, आईआईटी के स्नातक एस. श्रीकुमार कहते हैं, "हमारी बॉस औरत है लेकिन इसके कारण हमें कोई खास मुश्किल नहीं होती."

और किरण में कोई खास तब्दीली नहीं आई है. वे हमेशा से स्वतंत्र विचारों की, संकल्पवान और कर्मठ रही हैं. उनके इन गुणों में और निखार ही आया है. "मैं शादी से इनकार नहीं करती. अगर हो जाए तो ठीक है. लेकिन मुझे पति समझदार चाहिए. क्योंकि मैंने जो कुछ इतनी मेहनत से बनाया है उसे खो देने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूं." वे कहती हैं कि "मेरे पल्लू की गांठ तो काम से ही बंध गई है. लोग कहते हैं कि घर-बार बसा लेने का वक्त आ गया है. पर मैं कहती हूं कि शुक्रिया, मेरा घर तो बसा-बसाया है." —अनीता प्रताप

अक्सर औरतें सिर्फ औरत होने के नाते विशेष रियायतों की उम्मीद करती हैं. यह गलत है. स्त्रियों को समानता का व्यवहार करना चाहिए"

श्रीनिवास कुमार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभी दस साल पहले तक भी इसे खामखयाली कहकर खारिज कर दिया जाता था. लेकिन आर्थिक जोखिमों से भरपूर, पुरुषों के संपूर्ण वर्चस्व वाले इस मजबूत दुर्ग—व्यवसाय जगत—में भारतीय स्त्रियां धीमे-धीमे लेकिन मजबूती से कदम रखने लगी हैं. महिलाओं के लिए सर्वथा वर्जित इस क्षेत्र में यहां-वहां कामयाब या संघर्षरत स्त्री उद्यमियों की उपस्थिति नजर आने लगी है. यह स्वस्थ प्रवृत्ति उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और बदलते सामाजिक रवैये की जीवंत प्रतीक है. शहरी भारत आज नई शक्ल ले रहा है.

जैसा कि 34 वर्षीया किरण मोदी कहती हैं, "मेरी मां के समय में महिलाएं सिर्फ खरीदार हुआ करती थीं. आज वे खरीदार ही नहीं रहीं, विक्रेता भी हो गई हैं." मोदी दक्षिण दिल्ली में 'नेबरहुड स्टार' नामक विज्ञापनों का अखबार निकालती हैं. अमेरिकी शैली का यह आठ पेजी अखबार राजधानी में अपनी किस्म का अकेला है और दक्षिण दिल्ली के कोई 10,000 घरों में मुफ्त भेजा जाता है. स्थानीय जौहरी, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां और सिले-सिलाए वस्त्रों के विक्रेता इसमें अपने विज्ञापन देते हैं जिससे अखबार का खर्च चलता है. मोदी कहती हैं, "विज्ञापनदाताओं को लाभ होने से हमें भी फायदा हो रहा है." अखबार की सफलता के बारे में उनका कहना है कि "दिल्ली अब एक विशाल उपभोक्ता समाज में तब्दील हो गई है. ऐसा न होता तो मैं कामयाब न हो पाती."

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में महिला व्यवसायियों का व्यापक अध्ययन करने वाली यहां की लेडी इर्विन कॉलेज की सावित्री राममूर्ति के अनुसार इन उद्यमियों में से 40 फीसदी ने इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, सलाहकार सेवा, रसायन, सर्किट ब्रेकर, एंप्लीफायर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन उत्पादन जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रवेश किया. बाकी सिले-सिलाए वस्त्र, खाद्य-पदार्थ, चमड़ा, अंदरूनी सजावट, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक व्यवसायों में लग गईं.

गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिला उद्यमियों का इतने बड़े पैमाने पर प्रवेश बिलकुल हाल की घटना है. इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग पिछले दशक में ही तेज हुई. आईआईटी, दिल्ली के मानविकी और समाज विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉ. पूर्णिमा माथुर के अनुसार महिला उद्यमियों ने इस मांग की तरफ इसलिए भी ध्यान दिया क्योंकि उनके खुद के रवैये में भी बदलाव आता गया. वे कहती हैं, "महिलाएं पहले की बनिस्बत अब अधिक स्वतंत्र हो गई हैं, उपलब्धियों और कैरियर पर ध्यान देने लगी हैं, उनमें जानने की उत्सुकता और सृजन की क्षमता है, वे जोखिम मोल लेने के लिए भी तैयार हैं. वे अपने सामाजिक कामकाज का विस्तार करना चाहती हैं, उपलब्धि हासिल करना चाहती हैं और समाज से मान्यता पाना चाहती हैं."

समुचित आंकड़े न मिलने के कारण महिला उद्यमियों की बदलती प्रवृत्ति के आयामों का पता लगाना मुश्किल है. लेकिन यह परिवर्तन महानगरों में स्पष्ट है. और

सरपरवीन कौर

मधुमक्खियों का मोहपाश

मन बहलाव का तरीका बड़े उद्यम में बदल जाएगा और वे उसी में सारा समय व्यस्त रहा करेंगी यह सरपरवीन कौर ने सोचा भी नहीं था. मधुमक्खियां पालने का शौक ऐसा रंग लाया कि पिछले साल उन्होंने छह टन शहद का उत्पादन कर डाला. एक सैनिक की इस 34 वर्षीया खूबसूरत बेटी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनका वक्त मकान के पिछवाड़े पल रहीं 50,000 मधुमक्खियों के साथ गुजर जाया करेगा. वे कहती हैं, "शौक के बतौर यह शुरू हुआ पर अब मैं इसमें ही रम गई हूं."

1976 में सरपरवीन के पति पीटर सतवंत सिंह भी दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में चल रही अपनी पीएचडी छोड़कर जालंधर के नजदीक अपने फार्महाउस में जा बसे. यहां पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉ. ए.एस. अटवाल ने उन्हें इटली की मधुमक्खियों के करिश्मे की जानकारी दी. सरपरवीन की दिलचस्पी जाग उठी और वे मधुमक्खियों के प्रति समर्पित हो गईं. शुरू में उन्होंने मधुमक्खियों के पांच बाड़े डाले थे जो अब बढ़कर 250 हो गए हैं.

सरपरवीन और उनके पति वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खियां पालने वाले देश के एकमात्र उद्यमी हैं. उन्होंने पंजीकृत अनुसंधान और विकास शाखा भी खोल रखी है.

पति-पत्नी दोनों मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देते हैं. वे प्रशिक्षार्थियों को उपकरण, उपयुक्त जानकारी और मधुमक्खियां भी मुहैया कराते हैं. वे उनके द्वारा उत्पादित शहद खरीद कर उसे 'गोल्डन मिडास' लेबल के तहत बेचने की व्यवस्था भी करते हैं.

सरपरवीन अब पूरी तरह से शहद पर आधारित प्रसाधन सामग्री, पराग से निर्मित शुद्ध प्रोटीन की गोलियां और रॉयल जेली बनाने की योजना पर काम कर रही हैं.

यह काम उनकी जीवन शैली को माफिक भी पड़ता है. वे कहती हैं, "मां अगर कामकाजी हो तो घर में उसका विशेष सम्मान होता है." समस्या बस यही है कि मधुमक्खियों के कारण कोई नौकर उनके यहां नहीं टिकता.

—सिमरन भार्गव

मां *अगर कामकाजी हो तो घर में उसका विशेष सम्मान होता है"*

प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नलिनी शर्मा

साड़ियों के नए सोपान

नलिनी शर्मा किसी घरेलू ब्राह्मण स्त्री की तरह दिखती हैं. लेकिन गफलत में न पड़िए. इस सीधी-सादी काया के पीछे है एक धांसू उद्यमी, जिसके नाम की साड़ियों और परिधानों ने देश भर की महिलाओं का ध्यान आकृष्ट किया है. 300 से 1500 रु. कीमत वाली नलिनी साड़ियां मध्यम वर्ग के साथ-साथ अभिजात्य वर्ग की महिलाओं में भी बेहद लोकप्रिय हैं.

नलिनी का विवाह सुरेश शर्मा से 19 साल की उम्र में हो गया था. सौभाग्य से उन्हें ऐसा पति और परिवार मिला जिसने उनके व्यवसाय में उतरते ही उनका हाथ बंटाना शुरू कर दिया. नलिनी एक सूटकेस लेकर धंधे में उतर पड़ीं. वे दिल्ली के बाजारों में घूमतीं, आम तौर पर न मिलने वाली साड़ियां खरीदतीं और मित्रों-परिचितों में उन्हें बेच देतीं. लोगों को जैसे-जैसे पता चलता गया, उनकी साड़ियों की मांग बढ़ती गई. मांग इतनी बढ़ी कि उनको साड़ियां रखने, ग्राहकों को दिखाने के लिए एक छोटी दुकान किराये पर लेनी पड़ी.

1970 के आखिर में उन्होंने 50,000 रु. पगड़ी देकर दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक कोठरीनुमा खस्ताहाल दुकान किराये पर ले ली. नलिनी उन दिनों की याद करती हैं, "उस वक्त मेरे तीन बच्चे थे और मेरे बाहर रहने के दौरान पति को ही बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी."

होटलों में अपनी डिजाइन की प्रदर्शनियों की शुरुआत करने का श्रेय नलिनी को ही जाता है. वे कहती हैं, "मैं ऐसी पहली महिला हूं जिसने देश में अपनी डिजाइनों की प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा डाली." '70 के आखिर तक नलिनी अपनी डिजाइनें खुद तैयार करके उन्हें दर्जियों और वस्त्र निर्माताओं को मुहैया कराने लगीं.

आज उनकी सालाना बिक्री 1 करोड़ रु. की है. ओखला में उनका बड़ा भारी कारखाना है. नलिनी कहती हैं, "आज हमारे पास तकरीबन 4,000 डिजाइनें हैं और मैं हर हफ्ते में दो नई डिजाइनें बना लेती हूं. यदि पति साथ हो तो काम में और भी मजा आता है."

—इंद्रजीत बधवार

पति का सहयोग मिले तो काम में और भी मजा आता है"

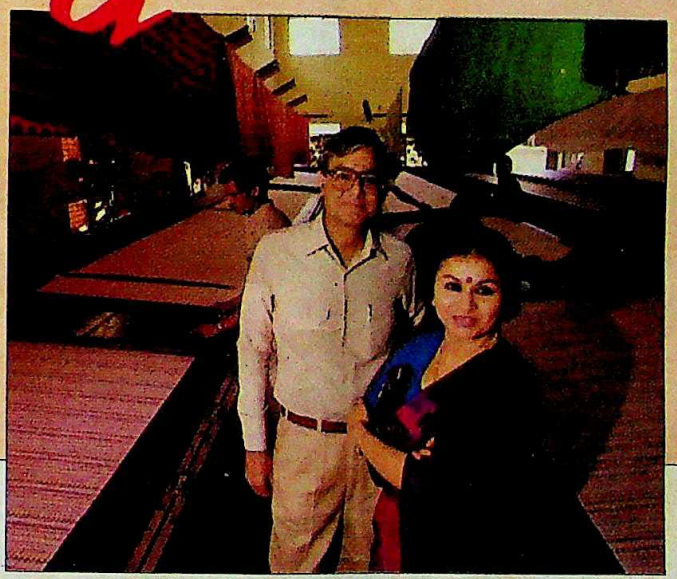

प्रशांत पंजियार

अपेक्षाकृत छोटे शहरों में भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं. इसके कुछ उदाहरण:

▶ हरियाणा की मूल निवासी कश्मीरी देवी ने अपनी भूगोल की किताब में पढ़ा था कि नगालैंड में असामान्य रूप से भारी वर्षा होती है. उन्होंने इस तथ्य पर गौर किया और कई साल बाद नगालैंड के दीमापुर में एक छाता कारखाना लगा लिया. एक दशक पहले जब उन्होंने 25,000 रु. की लागत से यह कारोबार शुरू किया तब वे नहीं जानती थीं कि कैसे उसे आगे बढ़ाएंगी. उस समय कारोबार दो लाख रु. का था. आज उनके पास 30 लाख रु. के आर्डर हैं. वे सिर्फ छाते के कारोबार से ही संतुष्ट नहीं हुईं. उन्होंने अपनी दुकान में फोटोस्टेट का काम भी शुरू कर दिया. आज उनकी दुकान में तीन आधुनिक कॉपीइंग मशीनें लगी हुई हैं.

▶ औद्योगिक रूप से पिछड़े बिहार में किसी महिला उद्यमी की तलाश रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह ही है. लेकिन यहां भी करीब 30 से 50 तक महिला उद्यमी हैं. इनमें से दो तो राज्य के चैंबर ऑफ कॉमर्स की सदस्या भी हैं. इनमें सबसे विशिष्ट मामला 45 वर्षीया पुष्पा चोपड़ा का है. वे एक इंजीनियर की पत्नी हैं. चौथी क्लास में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी. लेकिन बाद में निजी विद्यार्थी की हैसियत से पढ़ाई पूरी की और सातवें दशक के मध्य में अपना चोपड़ा उद्योग लगाया, जिसमें छोटे पैमाने पर बेल-बूटे की कढ़ाई की जाने लगी. वे याद करती हैं, "जब मैंने बेल-बूटे काढ़ी हुई पहली चादर बनाई तो हर कोई मुझ पर हंसने लगा, यहां तक कि मेरे पति भी परेशान होने लगे. यह वही रवैया था जिसने राज्य में कई महिला उद्यमियों का उत्साह ठंडा कर दिया है."

लेकिन वे सुबह से आधी रात तक अनवरत काम में जुटी रहतीं. आज उनका कारोबार लगभग 3 लाख रु. का हो गया है. उनकी बेल-बूटे काढ़ी हुई साड़ियां, बिस्तर की चादरें, कवर, तौलिया, परदे पूरे भारत में बिकते हैं. वे घर से ही व्यवसाय चलाती हैं. उनके यहां 20 महिलाएं काम करती हैं. वे अब अपने एक भतीजे के सहयोग से टेल्को और टिस्को जैसी बड़ी कंपनियों को मशीन के ऑटो कल-पुर्जे भी सप्लाई करती हैं. इसका सालाना कारोबार है 24 लाख रु. का.

▶ राष्ट्रीय युवा उद्यमी संघ की अध्यक्ष नीना मल्होत्रा की कामयाबी की कुंजी रही—छोटे पैमाने पर काम शुरू करना, पूरी शिद्दत से उसमें लगे रहना, व्यापार के दूसरे क्षेत्रों में लगातार हाथ आजमाते रहना और हमेशा ज्यादा बिक्री वाले बाजार को ध्यान में रखना. नीना दिल्ली के एक इंजीनियर की पत्नी हैं. उन्होंने 10,000 रु. की शुरुआती पूंजी से खराद (लेथ) मशीन लगाई और एक ट्रैक्टर कंपनी के लिए गियर रखने के पुर्जे बनाने लगीं. वे एक दिन में लगभग 1,000 कल-पुर्जे तैयार करती हैं. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में काम आने वाले प्लास्टिक के कल-पुर्जे उनका सबसे नया उत्पादन होगा. नीना अब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'कैरिंग ऐंड फारवर्डिंग एजेंसी' बनाने पर भी गौर कर रही हैं.

बंबई और दिल्ली में महिलाएं डिजाइन और विज्ञापन के क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से स्नातक प्रीति व्यास ने 500 रु. माहवारी प्रशिक्षण भत्ते से कैरियर शुरू किया था. अब उन्हें इतनी गंभीरता से लिया जाने लगा है कि वे कर्मशियल आर्ट्स गिल्ड के 10 पुरस्कार जीत चुकी हैं. उन्होंने 'सिने ब्लिट्ज' और 'स्पोर्ट्सवीक' के लिए डिजाइन बनाने के अलावा फिल्म 'उमराव जान' का 'लोगो' (चिन्ह) और कलकत्ता में स्ट्रीट साइन तैयार किया. दिल्ली की नफीज़ खिजर ने 20,000 रु. की लागत से खास तौर पर डिजाइन किए गए सिले-सिलाए वस्त्रों का कारोबार शुरू किया. कुछ ही वर्षों के भीतर उनके इस 'बानू क्रिएशन' नामक प्रतिष्ठान का कारोबार सालाना 10 लाख रु. का हो गया है.

तारा सिन्हा का नाम विज्ञापन जगत का पर्यायवाची बन गया है. लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वे 1985 तक खुद उद्यमी नहीं थीं. वे क्लेरियन एडवर्टाइजिंग में वरिष्ठ अधिकारी थीं. वहां अनबन हो जाने के बाद उन्होंने खुद का कारोबार शुरू कर दिया. वे कहती हैं, "फिर से जीवन शुरू करना, खास तौर पर 53 साल की उम्र में जटिल काम है. मेरा कोई सरपरस्त नहीं था. लेकिन ढेरों दोस्त थे जिनका मुझे खासा समर्थन मिला. मेरी जो खाने की मेज है, वहीं से हमने अपना नया जीवन शुरू किया." आज विज्ञापन के क्षेत्र में उनकी सेवाएं लेने वालों में डीसीएम टोयोटा, नेस्कैफे, मिल्कमेड, केयो कार्पिन, ग्रीन मैजिक प्लांट फूड जैसी बड़ी कंपनियां हैं. इस साल उनका कारोबार 7 करोड़ रु. तक पहुंचने की उम्मीद है.

उत्तर भारत में भी महिला उद्यमी आगे बढ़ रही हैं. लखनऊ में दो गृहणियों—40 वर्षीया उर्मिला राय और 26 वर्षीया नीता सिंह ने नौ-नौ हजार रु. मिलाए, पास की एक कॉलोनी में 300 रु. महीने पर एक कमरा किराए पर लिया, तीन अंशकालिक तकनीशियनों को रखा और 'मल्टीटेक' नाम की एक कंपनी शुरू कर दी. वे दरवाजे पर लगने वाली एक 'घंटी' बनाती हैं जिससे दरवाजा खोलने से पहले ही आगंतुक की आवाज सुनकर पता चल जाता है कि कौन आया है. इस जोड़ी ने साल भर पहले काम शुरू किया था. तब से वे 500 रु. कीमत के ऐसे 500 उपकरण बेच चुकी हैं. उर्मिला कहती हैं, "यह तो एक छोटी-सी शुरुआत है. लेकिन सभी बड़े व्यवसाय इसी तरह शुरू होते हैं."

महिला उद्यमियों की तादाद बढ़ने का कारण यह भी है कि सरकार और निजी संस्थान उनकी जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के सामाजिक जगत में परिवर्तन की जो तेज लहर आई, उसी का एक पहलू है उनका उद्यमियों के रूप में उभरना. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक हालांकि लड़कों की बनिस्बत ज्यादातर लड़कियां ही स्कूल की पढ़ाई-लिखाई अधूरी छोड़ देती हैं लेकिन

शहनाज़ हुसैन

जड़ी-बूटियों का जौहर

आत्मविश्वास, धैर्य, दृढ़निश्चय और सफलता का पर्याय बन चुकी 44 वर्षीया शहनाज़ हुसैन जड़ी-बूटियों से सौंदर्य प्रसाधन बनाने के कारण अंतरराष्ट्रीय हस्ती बन चुकी हैं. सातवें दशक के शुरू में शहनाज़ ने पिता से उधार लिए 35,000 रु. से दक्षिण दिल्ली में अपने फ्लैट के ही एक छोटे कमरे से काम शुरू किया था. साथ ही वे देश में घूम-घूमकर आयुर्वेदिक दवाओं का अध्ययन भी करती रहीं. उस वक्त उन्होंने त्वचा की सुरक्षा के लिए चंदनयुक्त क्रीम तैयार की थी. बावजूद इसके वे अपने क्लीनिक में न्यूयॉर्क के हेलेना रूबेंस्टीन और क्रिस्टिन वैल्माय ब्यूटी स्कूलों में सीखे परंपरागत सौंदर्योपचार ही दिया करती थीं.

शहनाज़ याद करती हैं, "लेकिन ग्राहकों की कमी तब भी नहीं थी क्योंकि भारतीय महिलाएं सौंदर्य के प्रति सचेत हो चली थीं. दूसरे सौंदर्योपचार केंद्रों में जहां फेशियल के छह रु. लिए जाते, मैं तीस रु. लेती. फिर भी ग्राहकी कम नहीं थी." आज उनकी कंपनी त्वचा के सौंदर्यवर्धन के लिए 55 तरह के उत्पाद तैयार करती हैं. शहनाज़ हर्बल की शाखाएं आज दूसरे 43 देशों में भी फैली हैं.

विदेश में उन्हें सबसे पहली कामयाबी लंदन के 'सेल्फ्रीजेस' में मिली. वहां चार साल पहले जब उन्होंने अपने सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री शुरू की तो पहले दो घंटों में ही 2700 पौंड का माल बिक गया. अब वे जापान में धूम मचा रही हैं. जापान में भारत महोत्सव के दौरान तोक्यो के शिबुज डिपार्टमेंटल स्टोर में तीन ही दिनों में लगभग 13 लाख रु. के जड़ी-बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन बिक गए.

"यह मैं सिद्ध कर देना चाहती थी कि मेरा अपना भी कोई वजूद है"

शहनाज़ कहती हैं कि वे जुनून की वजह से ही कामयाब हो पाईं. "पंद्रह साल में मेरी शादी हो गई. अगले ही साल बेटी नीलोफर का जन्म हुआ. उस उम्र में लगता था कि कुछ और करने को रह ही नहीं गया है. चूंकि मुझे कुछ कर दिखाने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए मैं साबित करना चाहती थी कि मेरा अपना भी कोई वजूद है." उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. —इंद्रजीत बधवार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुचिंत-नरेशबाला

कंप्यूटर का करिश्मा

सुचित आनंद और नरेशबाला गोयल दोनों अध्यापिकाएं थीं. स्कूली दिनों से मित्र रहीं इन दोनों का विवाह साधारण सरकारी कर्मचारियों से हो गया. दो साल पहले दोनों ने निजी कारणों से अपनी अध्यापकी छोड़ दी और खुद का ही कोई कारोबार शुरू करने का फैसला कर लिया.

नरेशबाला कहती हैं, "हम हाथ पर हाथ धरे घर पर नहीं बैठे रह सकते थे. पति ने भी हमेशा प्रोत्साहित किया. वे हमसे हमेशा कहते, अपने दायरे से बाहर निकलो और कुछ कर दिखाओ." और सचमुच उन्होंने कुछ कर दिखाया. उन्होंने अल्प अवधि का कंप्यूटर कोर्स किया और 'फिक्की' के एक प्रशिक्षण कोर्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना सीखा.

सुचित कहती हैं, "हमें लग गया कि अब हम अपनी कंपनी खोल सकते हैं." इसके बाद दोनों महिलाओं ने एक महीने तक बसों और तिपहियों में यात्रा कर कंप्यूटर के बाजार का सर्वेक्षण किया. सुचित पुराने दिनों की याद करती हैं, "मित्र कहते थे कि इनसे यह काम हो ही नहीं सकता. लेकिन अप्रैल 1987 में बचत के कुछ हजार रुपयों से हमने 'एलटेक' नामक कंपनी बना ली ताकि ग्राहकों और सरकार से पत्र व्यवहार करने में आसानी हो.

दिल्ली से बाहर दूरदराज औद्योगिक क्षेत्र में एक शेड में आज 'एलटेक' के 10 कर्मचारी काम करते हैं. यह कंपनी कंप्यूटर के 'की बोर्ड' और 'मॉनीटर्स' बनाती है. उनके सबसे बड़े खरीदार 'शिवा कंप्यूटर' और बंबई की 'एपटेक' हैं. नरेशबाला गर्व से बताती हैं, "शुरू में हमें तकनीकी सलाह की जरूरत थी लेकिन अब हम पूरी प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं. हमारा पहले साल का कारोबार तकरीबन 6 लाख रु. का होना चाहिए."

सुचित गर्व से कहती हैं, "आज जो कुछ भी है, हमारी अपनी कोशिशों का फल है. बैंकवाले हमें यह कहकर हतोत्साहित करते थे कि आप महिलाएं हैं और आपकी आड़ में आपके पति काम कर रहे हैं. लेकिन अब मैं अकेले जाती हूं. हममें आत्मविश्वास है. हमने कुछ हासिल किया है इसका एहसास हमें है."—**इंद्रजीत बधवार**

हममें आत्मविश्वास है. हमने कुछ हासिल किया है इसका एहसास भी हमें है"

प्रशांत पजियार

पिछले दशक के दौरान रोजगार के क्षेत्र में जाने वाली लड़कियों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है. यहां तक कि कॉलेजों में भी लड़कियां ऐसे पाठ्यक्रम चुन रही हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें. दिल्ली आईआईटी की डॉ. माथुर के मुताबिक एक दशक पहले ज्यादातर लड़कियां स्नातकोत्तर मानविकी और विज्ञान में दाखिला लिया करती थीं, आज वे इंजीनियरिंग जैसे स्नातक पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आने लगी हैं.

एक कामकाजी मध्यवर्गीय परिवार की 37 वर्षीया रंजनबेन दयालभाई पटेल को घरवालों ने स्वप्नदर्शी मान लिया था. लेकिन उद्यम विकास केंद्र से तीन महीने का पाठ्यक्रम पूरा करके रंजनबेन ने घरवालों को अचंभे में डाल दिया. उन्होंने राज्य वित्त निगम से 3 लाख रु. कर्ज लेकर 1981 में रबर का कारखाना लगा लिया. उनकी यह लघु इकाई देश की उन दो इकाइयों में है जो उष्मा प्रतिरोधक रबर के धागे बनाती है.

संपन्न परिवार की महिलाएं भी अपने धंधे पर खुद के व्यक्तित्व की छाप छोड़ने पर दृढ़संकल्प दिखाई पड़ती हैं. ज्योति पोद्दार अपने बच्चों के बड़े होने तक सामाजिक काम करती रहीं. फिर उन्होंने कलकत्ता की खस्ताहाल लॉयन ऐंड एडवर्ड्स ट्रेवल एजेंसी को अपने हाथों में ले लिया. जब उन्होंने उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की तो लगभग सभी पुरुष अधिकारियों ने विरोध किया. ज्योति ने तेजी से कार्रवाई की और प्रबंधक को बरखास्त कर खुद सारे विभाग देखने लगीं. उन्होंने रोजाना 12-12 घंटे काम किया. आज उनका कारोबार लगभग 40 लाख रु. का है. लेकिन ज्योति अफसोस जाहिर करती हैं, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादातर महिला उद्यमियों को शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है. उन्हें कोई प्रशिक्षित करने वाला नहीं होता, भले ही वे व्यावसायिक परिवारों की ही क्यों न हों."

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (फिक्की) के महिला संगठन की संयोजिका निश्चित अरोड़ा कहती हैं, "बिड़ला, पोद्दार, खेतान जैसे प्रमुख उद्योग घरानों की बहू-बेटियां उद्योगों में पांव जमाने के प्रांत बहुत गंभीर हैं. यह पीढ़ीगत परिवर्तन है. पारंपरिक मारवाड़ी घरानों की स्त्रियां घर की चारदीवारी से निकलकर अपनी पहचान बनाने में जुट गई हैं. फिर भी उन्हें हिसाब-किताब और औद्योगिक संबंधों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है और हमारा संगठन इन्हीं सब का विशेष प्रशिक्षण देता है."

पर यह संगठन महिला उद्यम को मान्यता देने और उसे आगे बढ़ाने वाला अकेला संगठन नहीं है. भारतीय स्टेट बैंक जैसे व्यावसायिक बैंकों ने भी विशेष महिला प्रकोष्ठ बना रखे हैं. बड़े शहरों के चारों तरफ फैल रहे औद्योगिक क्षेत्रों में 10 फीसदी जगह महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जा रही है. इतना ही नहीं, कर्ज देने वाली संस्थाएं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायती कर्ज और वित्तीय सहायता देने की भी योजनाएं बना रही हैं.

महाराष्ट्र में अहमदनगर की श्रीरामौर क्रेडिट सोसायटी ने अपने बोर्ड में सात महिला सदस्यों को निर्वाचित करके ग्रामीण महाराष्ट्र में महिला उद्यम के बीज रोप दिए हैं. कलकत्ता में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने महिलाओं को आर्थिक और बजट के विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए एक महिला अध्ययन दल बनाया है. कलकत्ता में करीब 100 महिला उद्यमी हैं और उनका सालाना कारोबार 35 करोड़ रु. का है. गुजरात चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने दो साल पहले अपनी पहली महिला शाखा खोली. उसमें आज 600 सदस्य हैं. इनमें से आधी निर्माता हैं और बाकी व्यापारी. पिछले दो वर्षों में गुजरात राज्य वित्त निगम ने खास योजना शुरू करके महिला उद्यमियों की लगभग 118 परियोजनाओं को 50 लाख रु. की सहायता दी.

दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद दक्षिण में संभवतः कर्नाटक में महिला उद्यमियों की संख्या सबसे ज्यादा है. वहां उद्योग और निर्माण के क्षेत्र में करीब 400 महिलाएं हैं. महिला व्यवसायी मधुरा चत्रपार्थी बताती हैं कि दूरसंचार, टायर रिट्रेडिंग, ट्रैक्टर ट्रेलर जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की विविध गतिविधियों के हिसाब से कर्नाटक का नाम सूची में संभवतः सबसे ऊपर है.

हालांकि व्यवसाय के लिए धन महत्वपूर्ण है लेकिन महिला उद्यमी व्यवसाय में जाने के लिए इसकी बनिस्बत दूसरी प्रेरणाओं को ज्यादा महत्व देती हैं. राष्ट्रीय युवा उद्यमी संघ की नीना मल्होत्रा का कहना है कि यह उपलब्धि की "वह सुंदर अनुभूति है जो रोजाना की समस्याओं से निबटने में समर्थ होने और अगली चुनौती का सामना करने के लिए सन्नद्ध अपने भीतर के मजबूत व्यक्ति को खोजने से आती है." अहमदाबाद के बाहर उद्यम संबंधी विकास संस्थान बनाने वाले डॉ. बी.जी. पटेल कहते हैं, "सिर्फ कारोबार के आधार पर इन महिलाओं की उपलब्धियों का आकलन करना गलत होगा. यह तो बंधनों के थोड़ा-बहुत टूटने से उभरी महिला उद्यमियों की पहली पीढ़ी है. इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है उसका महत्व बहुत है क्योंकि इन्हें दो प्रतिष्ठान—व्यवसाय और परिवार—देखने पड़ते हैं."

विवाहित महिला उद्यमियों के लिए घर और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाए रखना एक दिलचस्प अनुभव है. लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाएं मानती हैं कि वे बच्चों को ज्यादा समय न दे पाने की दोषी हैं. एक जवान बेटी की मां तारा सिन्हा कहती हैं, "आप हर समय सुपर महिला नहीं हो सकतीं." जड़ी-बूटियों से सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय ख्याति की शहनाज़ हुसैन कहती हैं, "आपको कुछ न कुछ बलिदान तो करना ही होगा. मेरा बेटा तो मां की सार-संभाल के बगैर ही बड़ा हो गया. यह बहुत तकलीफदेह है."

हरेक महिला उद्यमी ने कहा कि उनके

प्रभा खेतान

चमड़े की चकाचौंध

पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद प्रभा खेतान चाहतीं तो कहीं लेक्चरर हो जातीं पर उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया. उन्होंने मोटापा घटाने का केंद्र 'फिगरेट' खोल दिया.

इसके बाद प्रभा ने कुछ दूसरे व्यवसायों में भी हाथ आजमाने की सोची. चमड़ा निर्यात के कारोबार में उन्हें संभावनाएं दिखीं. वे बताती हैं, "मेरे घर वाले जोर दे रहे थे कि शादी कर लूं. पर स्कूल में मेरे बंगाली अध्यापक ने प्रोत्साहित किया कि मैं घरेलू मारवाड़ी औरत ही बनकर न रह जाऊं. परिवार में मैं हमेशा ही एक विद्रोहिनी की तरह रही." और इस विद्रोहिनी ने मोटापा कम करने के धंधे का पैसा चमड़े के छोटे-से कारोबार में लगाया और कलकत्ता की सबसे बड़ी चमड़ा निर्यातक बन गई. प्रभा अब जो कारखाना चलाती हैं उसमें तकरीबन 100 कर्मचारी काम करते हैं. उनका सालाना कारोबार करीब सात करोड़ रु. का है.

वे कहती हैं, "व्यापार-उद्योग के बारे में मर्दों ने एक तरह का भ्रम खड़ा कर दिया है कि यह काम इतना कठिन है कि औरतों के बस का नहीं." प्रभा के हिसाब से मर्दों में अच्छा व्यापारी बनने के लिए जरूरी कुछ विशेषताएं होती ही नहीं. वे बताती हैं, "व्यवसाय में मेरे साथ पुरुष सहयोगी भी हैं. एक बार जब हड़ताल हुई तब मैं अपने पुरुष सहयोगियों से ज्यादा बेहतर ढंग से वार्ता कर सकी. मैं उनसे प्यार से पेश आई और उनके साथ निजी तौर पर जुड़ी."

> **"मर्दों ने उद्योग-व्यापार के बारे में भ्रम खड़ा कर दिया है कि यह औरतों के बस का नहीं"**

कल्याण चक्रवर्ती

प्रभा से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि उनकी शादी हो गई तो उनके कारोबार का क्या होगा. उनके मुताबिक एक उद्यमी औरत को कई मुश्किलों से रू-ब-रू होना पड़ता है. खास तौर पर ग्राहकों से संपर्क साधने में. वे कहती हैं इस मामले में पुरुष खुलकर बात नहीं कर पाते. "पुरुष पुरुषों से ही सौदेबाजी के आदी होते हैं." वे मानती हैं कि अक्सर औरतों को खुद को मर्दों से बेहतर साबित करना पड़ता है. "इसका मतलब है ज्यादा कड़ी मेहनत और पक्की तैयारी. इसके लिए सिर्फ आधारभूत प्रशिक्षण और दृढ़ता की जरूरत होती है." —सुरजीत दासगुप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुनीता पीतांबर

कलाशिल्पों से कामयाबी

बंबई की सुनीता पीतांबर शायद देश की सबसे कामयाब कला व कला-शिल्प निर्यातक हैं. इस साल उनका कारोबार 1 करोड़ रु. तक पहुंच जाने की उम्मीद है. सुनीता ने अपना व्यवसाय सातवें दशक में शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने कमीजों की दुकान खोली. "मुझे तब लगा कि पूरी बंबई में पुरुषों के लिए कमीजों की एक भी दुकान नहीं है. मैंने कपडे और डिजाइन वगैरह खरीदे और उन्हें सिलवाकर बेचना शुरू कर दिया."

फिर जब नकलची भी मैदान में उतर आए तो वे कलाशिल्प के कारोबार में लग गईं. वे कहती हैं, "इसका कारोबार स्थानीय स्तर पर ही था. पर मैं इन चीजों को बड़े शहरों में लाई, इन्हें विदेश तक पहुंचा दिया. मैं भारतीय शिल्पियों से डिजाइन लाती हूं. वे अच्छे जानकार हैं. मैं भी उन्हें जरा-सा आइडिया भर दे देती हूं इसके लिए मुझे काफी घूमना-फिरना पड़ता है."

अमेरिका में 1985-86 में हुए भारत महोत्सव में सुनीता ने पोशाकों और गहनों की नुमाइश लगाई "असली सामान की, नकली की नहीं." 'शाही भारत की पोशाकें' नामक यह प्रदर्शनी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में लगी थी. वे बड़े संतोष से कहती हैं, "डायना ब्रीलैंड ने इसकी तारीफ में मुझे चिट्ठी लिखी."

सुनीता ने बंबई के सबसे बेहतरीन चीनी रेस्तरां की आंतरिक सज्जा भी की है. वे बताती हैं, "आंतरिक सज्जा के लिए ऐसा महान वस्तुशिल्पकार चाहिए जो जगह और सतहें तैयार कर सके. मैं हफीज कंट्रैक्टर के बिना चाइना गार्डन में कुछ न कर पाती. किसी भी झरोखे या दीवार पर लगे चित्र को देखकर आप मुझे याद किए बिना न रह सकेंगे."

उनकी शिकायत है कि बहुत-सी "कामचलाऊ चीजों को भी अब काफी गंभीरता से लिया जाने लगा है. मैं शिल्प में अपनी जान डाल देना चाहती हूं ताकि हर कोई इसका दीवाना हो जाए. महान चीजों को खरीदना प्यार करने की तरह है जिसके लिए सिर्फ दीवानगी और समझदारी की जरूरत होती है." —सलिल त्रिपाठी

"महान चीजों को खरीदना प्यार करने की तरह है जिसके लिए सिर्फ दीवानगी की जरूरत होती है"

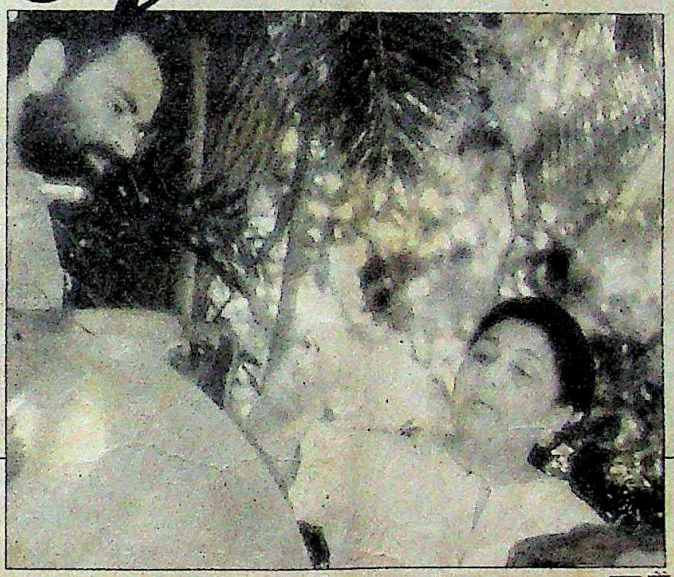

शांतनु शोरे

उद्यम में पति और परिवार का सहयोग बहुत ही अहम रहा. नीना मल्होत्रा कहती हैं, "पति के सहयोग और मंजूरी के बिना कोई भी महिला उद्यमी सफल नहीं हो सकती." लक्मे कॉस्मेटिक्स की प्रमुख साइमन टाटा कहती हैं, "यदि पति का रुख सहयोगी न हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है." पारंपरिक संयुक्त परिवार अपनी बहू के व्यवसाय शुरू करने पर भौंहें तान सकता है तो दूसरी ओर उसके लिए बहुत मददगार भी साबित हो सकता है. बहुधा यही देखा जाता है कि ऐसा परिवार मदद ही करता है.

युवा और उन्मुक्त विचारों की महिला उद्यमी आम तौर पर शादी की बनिस्बत व्यवसाय को अहमियत देती हैं. करोड़ों रुपए का एंजाइम (कण्वक) उत्पादन उद्योग चलाने वाली बंगलूर की 34 वर्षीया किरण मजूमदार कहती हैं, "मेरे पल्लू की गांठ तो काम से ही बंध गई है. जब लोग मुझसे कहते हैं कि यह आपके गृहस्थी बसाने का समय है तो मैं जवाब देती हूं कि शुक्रिया, मैं अच्छी तरह बस गई हूं." बंबई में 1983 में 'ग्राफिटेक्चर' नाम से व्यवसाय शुरू करने वाली सफल डिजाइनर 30 वर्षीया उर्शिला केरकर कहती हैं, "मैं कैरियर और शादी को विकल्पों के रूप में नहीं देखती. मेरी मां की शादी 19 बरस की उम्र में हो गई थी पर मैं वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी. मैं मरने के दिन तक काम करते रहना चाहती हूं."

हालांकि ज्यादातर महिला उद्यमी शादी के मामले में केरकर के इस विचार से सहमत नहीं हो सकतीं. लेकिन जिस तरह से केरकर कामकाज संभालती हैं, उससे वे निश्चित रूप से सहमत होंगी. महिलाएं मानती हैं कि थोक विक्रेताओं, खरीदारों, बैंकरों तथा सेल्समैनों की इस दुनिया में मर्दों की अपेक्षा उनके साथ अच्छा विनम्र व्यवहार किया जाता है. लेकिन दूसरी तरह की कई समस्याएं भी हैं. एक समस्या तो सचमुच गंभीर है. अंतरराष्ट्रीय व्यापारी रीना सिंह कहती हैं, "मैं इस व्यवसाय में लगी कुछेक महिलाओं में हूं. लेकिन मुझे अपनी विश्वसनीयता जमाने में ही तीन साल लग गए. और जब मैंने अधिकारियों को कायल कर दिया कि मैं अपने क्षेत्र के बारे में उनसे ज्यादा जानती हूं तो एक दूसरी ही समस्या खड़ी हो गई. वह समस्या थी पुरुषों के अहं की."

बैंक, यहां तक कि महिला प्रकोष्ठ वाले बैंक भी कर्ज लेने वाली महिलाओं को संदेह की निगाह से देखते हैं. इसकी वजह उनका यह विश्वास है कि महिलाएं अपना व्यवसाय छोड़कर फिर गृहिणी बन जाएंगी. स्वतंत्र रूप से व्यवसाय शुरू करने का इंतजार कर रही किसी महिला को कर्ज लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कर्ज की कीमत के बराबर जो संपत्ति वह बैंक के जिम्मे करना चाहती है वह आम तौर पर पति की होती है. इस तरह के मामले में वित्तीय संस्थान पतियों पर जोर देते हैं कि वे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्षाबेन शाह

गृहिणी भी, उद्यमी भी

तकरीबन 10 साल पहले 48 वर्षीय वर्षाबेन शाह व्यवसाय जगत में क्या उतरीं, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई. आज वे असित प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (सालाना कारोबार 60 लाख रु.) और दर्शित फिल्म प्रिंटर्स (कारोबार 40 लाख रु.) की उपाध्यक्ष हैं. पति भारत शाह ने जमे-जमाए धंधे की ओर ध्यान देना बंद करके जब सिंथेटिक उद्योग में उतरने का फैसला कर लिया तो वर्षाबेन ने दो छोटी औद्योगिक इकाइयां अपने हाथ में ले लीं. उनके द्वारा असित प्लास्टिक का जिम्मा संभालने के चार साल बाद बैंकों ने उसे एक आदर्श लघु इकाई का दर्जा दे दिया. कंपनी को कर्मचारियों की सबसे कम गैर-हाजिरी के लिए पुरस्कृत किया गया.

कर्मचारियों से व्यवहार करने का वर्षाबेन का अपना खास अंदाज है. वे कर्मचारियों को सत्यनारायण की कथा और दूसरे सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल करती हैं. इसका परिणाम यह है कि उनकी इकाई में कभी कोई गंभीर संकट नहीं आया. वहां अभूतपूर्व औद्योगिक शांति है.

वे सुबह छह बजे उठकर अपने कामों में जुट जाती हैं. नाश्ता खुद तैयार करती हैं, दूसरे घरेलू काम निबटाती हैं और रसोइए को दोपहर के खाने की हिदायतें देती हैं. 10.30 बजे वे दफ्तर जाती हैं और भोजन के वक्त 1.30 बजे घर लौटती हैं. दोपहर बाद 3 बजे से काम में फिर जुट जाती हैं. और शाम 6 बजे घरेलू कामों में हाथ बंटाने के लिए वापस घर आ जाती हैं.

"बच्चे कभी-कभी उपेक्षित महसूस करते हैं. लेकिन जिम्मेदारियों से बचा भी तो नहीं जा सकता"

वे कहती हैं, "हां, कई बार काम का बोझ महसूस होता है और मेरे तीनों बच्चे कभी-कभी खुद को उपेक्षित भी महसूस करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से बचा भी तो नहीं जा सकता."

वर्षाबेन पर इस वक्त 2 करोड़ रु. की कंपनी के विस्तार की बड़ी योजना की जिम्मेदारी है. इसे वे व्यक्तिगत रुचि लेकर कर रही हैं. जल्द ही वे बहुस्तरीय प्लास्टिक फिल्में और तरल पदार्थों को पैक करने की प्लास्टिक थैलियों का भी उत्पादन शुरू कर देंगी.

—उदय माहूरकर

साझीदार बन जाएं.

अखिल भारतीय प्रबंधन संघ की मालविका शॉ कहती हैं, "व्यवसाय या उद्योग जगत में कदम रखने के साथ ही महिलाओं के लिए परेशानियां शुरू हो जाती हैं. यदि आप महिला हैं, किसी लाइसेंस या कर्ज के लिए आवेदन कर रही हैं और उसके लिए फार्म भर रही हैं तो उसमें पहला सवाल ही यह होता है कि आप किसके बेटे हैं? ऐसी स्थिति में बताइए आप क्या करेंगे?"

हालांकि कोई पुरुष व्यवसायी दूसरे पुरुष व्यवसायी के साथ खाने-पीने के लिए बाहर जा सकता है. लेकिन अगर कोई महिला किसी पुरुष को बाहर चलने के लिए कहे तो लोगों की भौंहें तन जाती हैं, संबंध को लेकर छींटाकशी शुरू हो जाती है. ज्यादातर महिला उद्यमियों के मुताबिक, दूसरी बड़ी परेशानी है बिलों की वसूली के लिए दौड़धूप करना. सरकारी बाबू और निजी व्यापारी बिल दबाकर बैठ जाते हैं और पुरुषों के बजाय महिलाओं को ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाएं अदालत के पचड़े में पड़ने से कतराती हैं. डिजाइनर उर्शिला कहती हैं, "हमने नौ महीने तक लगभग धर्मार्थ ही काम किया क्योंकि जिन बड़े लोगों के लिए हमने पोस्टर डिजाइन किए, उन्होंने पैसे दिए ही नहीं."

लेकिन ज्यादातर महिला उद्यमियों का मानना है कि उनके ज्यादा कामयाब और अनुभवी होने से रूढ़िवादी धारणाएं और सेक्स संबंधी पक्षपात खत्म हो जाएगा. साइमन टाटा कहती हैं, "आप इन बातों को एकाएक खत्म नहीं कर सकते. बदलाव अब शुरू हुआ है. यह एक स्वाभाविक क्रिया है." लेडी इर्विन कॉलेज की राममूर्ति कहती हैं, "हमें याद रखना चाहिए कि अगर उद्यम में संघर्ष का तत्व न हो तो उद्यम की धारणा ही खत्म हो जाएगी. महिलाओं को समस्याओं का सामना बड़े साहस से करना चाहिए और लगातार आगे बढ़ना चाहिए."

कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय महिला उद्यम परिदृश्य अभी भी लघु और मझोले उद्योग के स्तर का है. नए पुरुष उद्यमियों के लिए तो टाटा, बिड़ला, मफतलाल या अंबानी की तरह के कई आदर्श हैं जबकि महिला उद्यमियों के साथ यह बात नहीं. उनके सामने तो एक-दो आदर्शों को छोड़ और कोई है ही नहीं. लेकिन कोई शहनाज़ हुसैन, कोई किरण मजूमदार आज व्यवसाय जगत में धूमकेतू की तरह उभर तो रही ही हैं. इसलिए महिला उद्यमियों के सितारे बुलंदियां छू सकते हैं. सच तो यह है कि भारत की महिला उद्यमी आज पेटीकोट, पापड और अचार की दहलीज पार कर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्यवसाय जगत की तमाम विधाओं में दृढ़ता से अपने पांव जमा रही हैं.

—इंद्रजीत बधवार, अनीता प्रताप, उदय माहूरकर, सलिल त्रिपाठी और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कामयाब बाजी

खबर है कि हिंदुजा बंधुओं ने एक और औद्योगिक बाजी जीत ली है. पिछले महीने हिंदुजा घराने ने ब्रिटिश कंपनी हैरिसंस ग्रीनफील्ड को खरीदने का करार कर लिया. कोचीन की हैरिसंस मलयालम में इस ब्रिटिश कंपनी के 40 फीसदी शेयर हैं. अशोक लेलैंड और एन्नूर फाउंड्रीज को खरीदने के बाद चारों हिंदुजा भाइयों की यह पहली बड़ी सफलता है.

बताया जाता है कि हिंदुजा बंधुओं ने हैदराबाद की आईडीएल केमिकल्स में नाइट्रो नोबेल के 29 फीसदी शेयर भी खरीदने का सौदा कर लिया है. दो साल पहले हिंदुजा बंधुओं ने डॉ कंपनी से आईडीएल के 10 फीसदी शेयर खरीदे थे जबकि उसी समय नाइट्रो नोबेल ने 29 फीसदी शेयर खरीदे थे. लेकिन अब नाइट्रो नोबेल ने (जिसे हाल ही में नार्वे की डायनो ने खरीद लिया) इन शेयरों को बेच देने का फैसला किया है.

जूतों के अलावा

लगता है जूता कंपनी बाटा में काफी उथलपुथल चल रही है. इसे नए किस्म के जूते बनाने के लिए जर्मनी की एडिडास कंपनी से करार करने की मंजूरी सरकार ने हाल ही में दे दी. बाटा कंपनी अब घड़ी, इत्र और कपड़े जैसी वस्तुओं के कारोबार में भी हाथ-पांव पसारने की सोच रही है. सत्तर के दशक के आखिर में उसने कमीजें बेचने के लिए मफतलाल से करार किया था. लेकिन बाजार में इन कमीजों की मांग न होने से वह पीछे हट गई.

वैसे, बाटा कंपनी को एडिडास से करार इस शर्त पर करने दिया गया है कि वह 33 फीसदी माल का निर्यात करेगी. लेकिन वह इसमें 8 फीसदी रियायत की मांग कर रही है क्योंकि करोना साहू को (जिसका प्यूमा से करार है) 25 फीसदी निर्यात की अनुमति मिली है. बाटा ने कुछ समय पहले जब एडिडास से करार किया था तो सरकार ने 75 फीसदी निर्यात की शर्त रखी थी.

'हार्ड' बनाम 'सॉफ्ट'

वाणिज्य संघों वाली राजनीति का रोग अब कंप्यूटर उद्योग को भी लग गया है. कुछ साल पहले मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (मेट) के बनने के बाद से ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियां यह महसूस कर रही थीं कि उनके साथ सौतेला बरताव किया जा रहा है. नतीजतन, सॉफ्टवेयर निर्माताओं की जरूरतों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देने के लिए अब एक नई संस्था नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐंड सर्विस कंपनीज (नैस्कोम) बनाई गई है. हालांकि 'मेट' को अभी भी उम्मीद है कि वह 'नैस्कोम' को अपने मातहत रखेगी, लेकिन यह संभव नहीं लगता. इसकी वजह है, हार्डवेयर की बनिस्बत सॉफ्टवेयर व्यवसाय में तेजी की उम्मीद.

'इंस्टैंट' जंग

इंस्टैंट कॉफी के बाजार में एक नई जंग छिड़ने जा रही है. 'इंडोडैन' की (जिसने हाल ही में बड़े जोर-शोर से गोल्ड कैफे को बाजार में उतारा था) योजना अब बाजार में दो और नए ब्रांड उतारने की है. एक तो कम कीमत वाली कॉफी होगी और दूसरा, कॉफी-चिकरी मिश्रण. इसका मतलब यह कि फूड स्पेशियलिटीज को अब और कड़े मुकाबले का सामना करना होगा. इसकी इंस्टैंट कॉफी के तीन ब्रांडों ने फिलहाल 60 फीसदी बाजार पर कब्जा कर रखा है. इसी तरह ब्रुक बांड पर भी दबाव बढ़ेगा जिसका 'ब्रू' (कॉफी-चिकरी का मिश्रण) बाजार में सबसे अधिक बिकता है.

तेल की धीमी धार

छठी योजना अवधि (1980-85) में तो पेट्रोलियम क्षेत्र को भारी कामयाबी मिली मगर वर्तमान योजना अवधि में इसके लिए मामला उलट गया लगता है. पिछले दो वित्तीय वर्षों में से हरेक में तेल का उत्पादन लक्ष्य से थोड़ा-सा कम ही रहा है. लेकिन 1987-88 में उत्पादन में खासी गिरावट आई. इसी के साथ-साथ पिछले साल तेल का आयात लगभग 50 फीसदी बढ़ गया. इस वर्ष तेल का आयात और भी बढ़ने की उम्मीद है. यदि

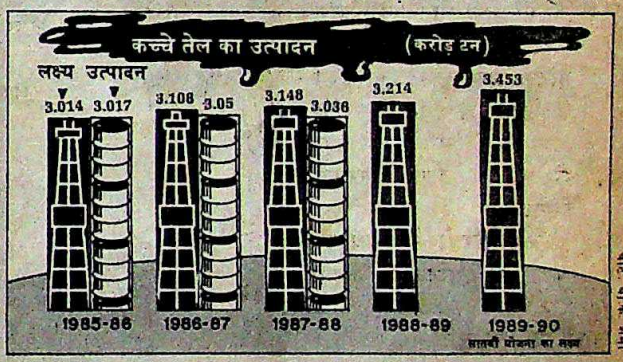

तेल उत्पादन में कोई नाटकीय वृद्धि न हुई तो 1989-90 तक सातवीं योजना का 3.453 करोड़ टन का उत्पादन लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद कम ही है.

पुराने प्रस्ताव पर विचार

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ओडीसा के दैतरी में इस्पात कारखाना लगाने के अपने आठ साल पुराने प्रस्ताव पर फिर विचार करने जा रहा है. शुरू के प्रस्ताव में परंपरागत तकनीक के इस्तेमाल से 30 लाख टन का कारखाना लगाने की योजना थी. ब्रिटिश साझेदार से मतभेद और आर्थिक समस्याओं के कारण इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल देना पड़ा था. अब नए प्रस्ताव के तहत अपेक्षाकृत छोटा स्पांज इस्पात कारखाना (उत्पादन क्षमता 8 और 10 लाख टन के बीच) लगाने की है. उम्मीद है कलकत्ता की दस्तूर ऐंड कंपनी इसकी व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करेगी. गुजरात में एक स्पांज इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में पहले से ही लग रहा है. दूसरे निजी उद्यमी भी विभिन्न राज्यों में इस्पात कारखाना लगाने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल के इच्छुक बताए जाते हैं. 'सेल' का विश्वास है कि भविष्य में मांग के अनुमान को देखते हुए उसकी यह परियोजना फायदेमंद साबित होगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

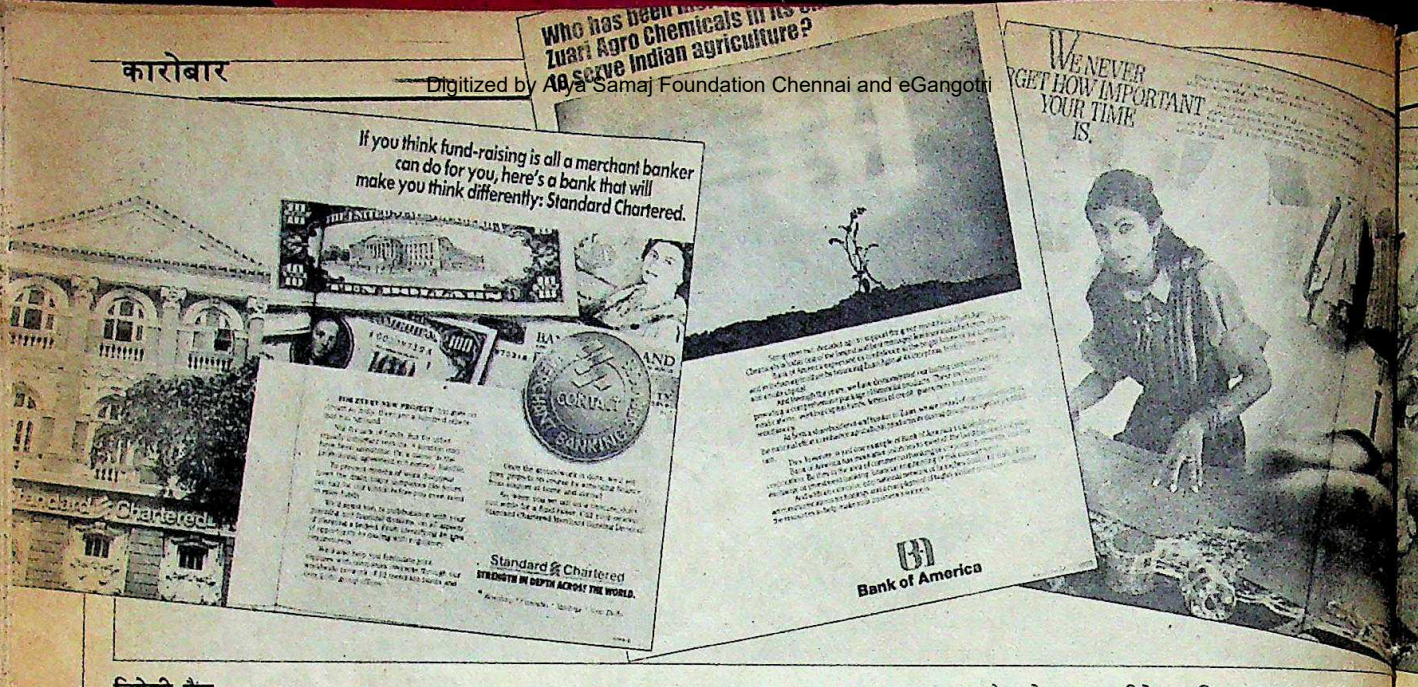

विदेशी बैंक

नए क्षेत्रों में प्रवेश की होड़

धंधा बढ़ाने के लिए कई तरह की लाभदायी योजनाएं

भारतीय बैंक व्यवस्था में उनकी केवल 3 फीसदी की हिस्सेदारी है. पूरे देश में उनकी 150 से कम शाखाएं हैं जबकि भारतीय बैंकों की तकरीबन 50,000 शाखाएं हैं. इसके बावजूद देश में काम कर रहे दो दर्जन विदेशी बैंक जोरों से धंधा कर रहे हैं और खूब पैसा बना रहे हैं.

सात विदेशी बैंकों ने भारत में अपनी उपस्थिति का आभास कराते हुए 1986 में 61.7 करोड़ रु. का मुनाफा कमाया. हालांकि पिछले साल इसमें कमी आई लेकिन उनका धंधा हर दृष्टिकोण से बढ़ता गया. बढ़ते धंधे से आकर्षित होकर दूसरे विदेशी बैंक भी भारत में आने के लिए सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं.

सिटी बैंक, ग्रिंडलेज, हांगकांग बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका सरीखे बैंक प्रचार अभियान छेड़ रहे हैं (उन्होंने पहले कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी); कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली शुरू कर रहे हैं; व्यक्तिगत बैंकिंग की सेवा देकर उच्च वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं तथा कार और स्कूटर के लिए कर्ज देने की पेशकश करके मध्यम वर्ग को लुभा रहे हैं.

ये विदेशी बैंक न सिर्फ बैंकिंग के नए विचारों को हवा दे रहे हैं बल्कि सहायक कंपनियां खोलने के लिए वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को भी पटा रहे हैं. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शेयरों की दलाली करने वाली फर्म खोलने की इजाजत पाने के वास्ते आवेदन करने की तैयारी कर रहा है; ग्रिंडलेज जोखिम उठाने वाला पूंजी कोष बनाने पर तुला है; एक और बैंक लीजिंग उपक्रम का प्रवर्तन करना चाहता है तो दूसरा बैंक साझा कोष् बनाना चाहता है. सिटी बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सहायक कंपनी पहले से चला रखी है.

विदेशी बैंक नित नए परिवर्तन कर रहे हैं. जैसे बड़े करारों के सिलसिले में ब्याज और मुद्रा के बदल की दरें बढ़ा दी गई हैं; टैक्स बचाने के लिए 'जीरो कूपन बांड' सरीखी निवेश की नई योजनाएं पेश की जा रही हैं और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए शेयर जारी करने के नए तरीके सुझाए जा रहे हैं. नैना लाल (ग्रिंडलेज) का कहना है, "कंपनियां अपना पैसा दाबे बैठी रहती हैं. वे उसका बहुत इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करतीं. पर विदेशी बैंक नए विचार रख रहे हैं, इससे जागरूकता बढ़ रही है."

जैसे ही कोई बैंक कोई नई योजना बनाता है दूसरे बैंक या तो उसकी नकल कर लेते हैं या फिर किसी नई सुविधा की पेशकश करते हैं. जैसा कि सिटी बैंक के पी.एन. विजय का कहना है, "किसी योजना की नकल शुरू होते ही लाभ की मात्रा घट जाती है. इसीलिए हम नए विचार लाने के लिए सिर खपाते रहते हैं." चेज़ मैनहटन के उपाध्यक्ष सुधीर देसाई इससे सहमत हैं, "भारतीय बैंकों ने कभी कोई नई पहल नहीं की."

विदेशी बैंकों की बहुप्रचारित नई सुविधा ऑटोमैटिक टेलर मशीनों (एटीएमएस) की है. फिलहाल ये इलेक्ट्रानिक मशीनें सिटी और हांगकांग बैंकों में ही लगी हैं. इनके जरिये उपभोक्ता चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवा हासिल

सात बड़े विदेशी बैंक

ग्रिंडलेज, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ क्रेडिट ऐंड कॉमर्स इंटरनेशनल और हांगकांग बैंक

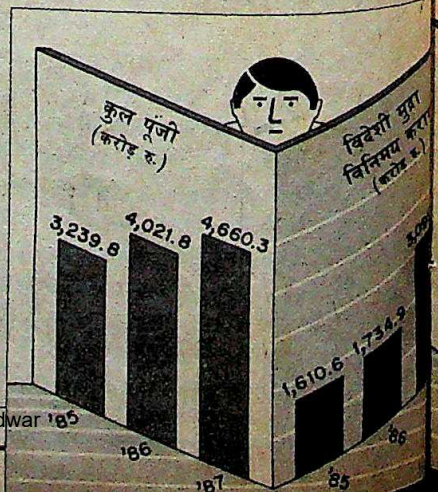

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

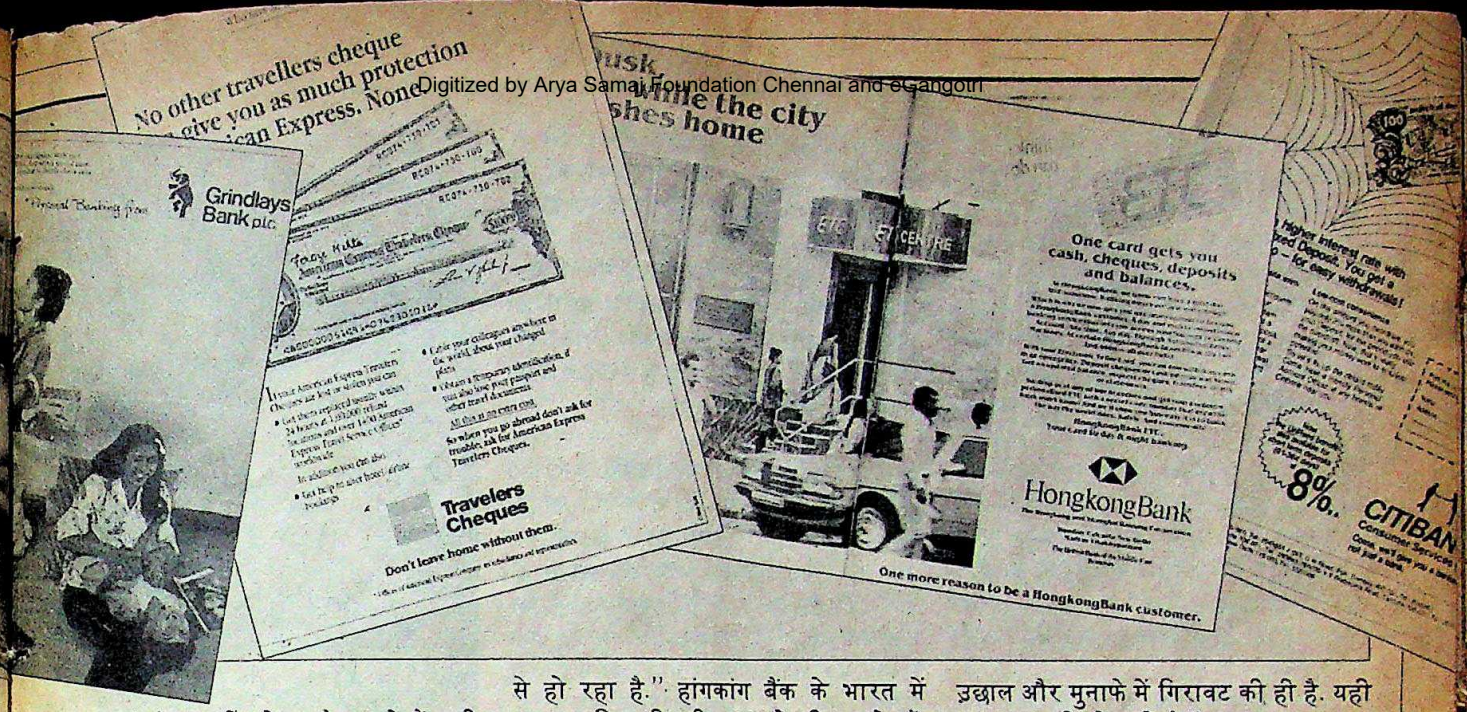

कर सकते हैं. अब ग्रिंडलेज और दूसरे बैंक भी यह मशीन अपनाने की योजना बना रहे हैं. जबकि विजया और बैंक ऑफ इंडिया सरीखे भारतीय बैंक एटीएमएस सुविधा साझे तौर पर उपलब्ध करवाने के लिए विदेशी बैंकों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं. सिटी बैंक के उपाध्यक्ष जे. राव तो रिजर्व बैंक की अनुमति मिल जाने पर एटीएमएस सेवा अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों तक पर उपलब्ध करवाने को तैयार हैं.

विदेशी बैंकों की गतिविधियां एकाएक बढ़ जाने की कई वजहें हैं. बाहरी हवा के लिए अपनी खिड़कियां खोलने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था; विदेशी व्यापारिक कर्जों की बढ़ती संख्या; भारत में धंधा खोलने वाले आप्रवासी भारतीयों की सेवा; कंपनी क्षेत्र की बढ़ती जरूरतें और समृद्धि की दहलीजें लांघता मध्यम वर्ग. बैंक ऑफ अमेरिका के उपाध्यक्ष चितरंजन कौल कहते हैं, "1985 से परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और अब बैंक गतिविधियों का विस्तार बेहद नियंत्रित ढंग से हो रहा है." हांगकांग बैंक के भारत में मुख्य अधिकारी सी.आर. सेल्बी कहते हैं, "सरकार अब ज्यादा उदार है और विदेशी बैंकों को भारत भविष्य का बेहद संभावनाओं भरा बाजार नजर आ रहा है."

विदेशी बैंकों की भारत में बढ़ती दिलचस्पी की एक वजह मुनाफे का स्तर भी है. यहां मुनाफे का स्तर संसार भर के 0.5 फीसदी के मुकाबले तकरीबन 3 फीसदी है. कई दूसरी वजहों से भी भारतीय बैंकों के मुकाबले विदेशी बैंकों का मुनाफा काफी ज्यादा रहता है. लेकिन बढ़ती प्रतियोगिता की वजह से विदेशी बैंकों का मुनाफा अब कम होने लगा है. अब उन्हें ग्राहकों के निवेश पर ज्यादा मुनाफा देना पड़ता है. इसके बावजूद उनके धंधे में बढ़ोतरी ही हो रही है. मुनाफा एक और वजह से भी कम हुआ है. अब मैदान में ज्यादा खिलाड़ी है और ग्राहक अब देखते हैं कि बैंक उन्हें क्या देने जा रहा है. बैंक ऑफ अमेरिका के एक उपाध्यक्ष का कहना था, "संसार भर में बैंकिंग की प्रवृत्ति धंधे में उछाल और मुनाफे में गिरावट की ही है. यही बात यहां भी हो रही है."

भारत के विदेशी बैंकों ने परंपरागत तौर पर कंपनी व्यापारिक बैंकिंग पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है लेकिन सिटी बैंक ने दिखा दिया है कि आम बैंकिंग के क्षेत्र में भी कामयाबी से उतरा जा सकता है. उधर बैंक ऑफ अमेरिका उच्च वर्ग को आकर्षित करने में लगा हुआ है. इसने बड़े उपभोक्ताओं के बैंक संबंधी कार्यों के लिए उनको व्यक्तिगत तौर पर बैंकिंग अफसरों की सेवाएं प्रदान की हैं. सिटी बैंक ने मध्यम वर्ग को खासी तरजीह दी है. यह फैसला बैंक ने अपनी संसार भर की शाखाओं के आम बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लिया है. लेकिन सिटी बैंक के राव और उनके सहयोगियों ने कई नई योजनाओं की नींव भी रखी है (निजी कर्जे, टेलीफोन कॉल पर बैंक सेवा आदि). राव कहते हैं, "तीन साल पहले जब मैं भारत वापस आया तो हमारे बैंक में उपभोक्ता बैंकिंग विभाग तक नहीं था. अब हम अपने मुनाफे का 25 फीसदी भारत में ही कमाते हैं." आप्रवासी भारतीयों द्वारा सिटी बैंक में जमा रकम पिछले 30 महीनों में 27 करोड़ से एकदम बढ़कर 400 करोड़ रु. हो गई है.

पुराने और अपेक्षाकृत सुस्त पड़े रहने वाले ब्रिटिश बैंक भी इस नई दौड़ में शामिल हो गए हैं. ग्रिंडलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी मजदूर यूनियनों से समझौता करके बैंक की शाखाओं में बड़े पैमाने पर कंप्यूटरों का इस्तेमाल करने का रास्ता साफ कर दिया है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड के भारत में मुख्य प्रबंधक मैगनस ई. स्टर्लिंग का कहना था, "हम अगले तीन वर्षों में अपनी चौबीसों शाखाओं का आधुनिकीकरण कर देंगे." ग्रिंडलेज के क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण एशिया) जी.जी. हॉवर्ड

चार्ट: बी.के. शर्मा

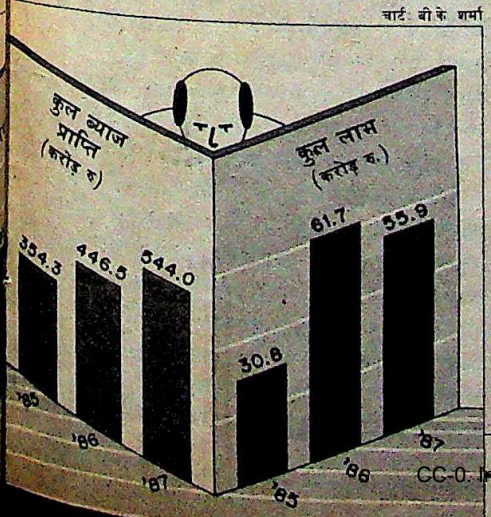

विदेशी बैंकों को भारत भविष्य का बेहद संभावनाओं भरा बाजार नजर आ रहा है, लिहाजा वे यहां आने के लिए सरकार के दरवाजे खटखटा रहे है. पहले से जमे विदेशी बैंक अब अपना पांव पसारने में जुटे हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहते हैं, "कंप्यूटरीकरण पूरा होते ही हम नई सेवाएं देने की सोच रहे हैं. भारत में सबसे ज्यादा शाखाओं वाला विदेशी बैंक होने के नाते हम शाखाओं के अपने इस विशाल तंत्र का भरपूर फायदा उठाएंगे."

इधर ये बैंक अपने पांव पसार रहे हैं और उधर दूसरे अनेक बैंक भारत में दाखिल होने की जुगत भिड़ा रहे हैं. सरकार और रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों को उतनी ही शाखाएं खोलने की अनमुति देते हैं जितनी भारतीय बैंकों को विदेशों में अपनी शाखाएं खोलने दी जाती हैं. लेकिन बैंकों के दबाव की वजह से (मसलन ड्यूश बैंक द्वारा पिछले महीने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जर्मनी यात्रा के दौरान अनुरोध) सरकार कुछ नरम पड़ती दिखती है पर रिजर्व बैंक का रुख अभी नरमी का नहीं है.

भारत के कुछ प्रमुख बैंक इससे चिंतित हैं. लेकिन कुछ दूसरे दार्शनिक मुद्रा में कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आर. श्रीनिवासन ने

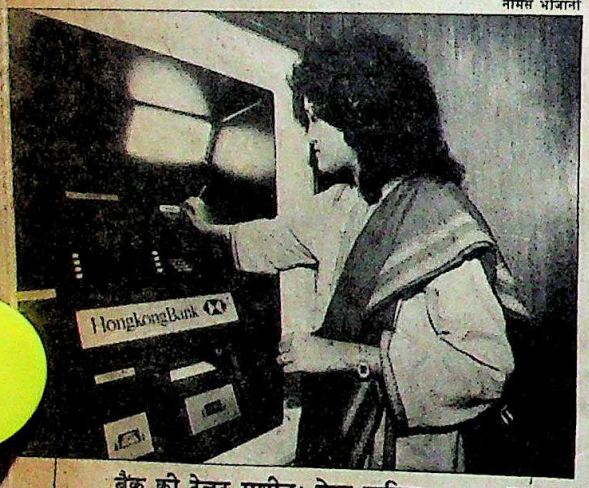

नासस भोजानी

बैंक की टेलर मशीन: सेवा हाजिर

'इंडिया टुडे' को बताया, "व्यापारिक बैंकिंग तक में भारतीय बैंक 80 से 90 फीसदी तक का धंधा करते हैं और खूब चांदी काट रहे हैं. विदेशी बैंक हमारे आगे बौने हैं."

लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष डी.एन. घोष इतने आशावादी नहीं हैं. वे कहते हैं कि कभी-कभार सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी इस तरह का बरताव करती हैं मानो विशिष्ट बैंक सेवा केवल विदेशी बैंक ही उपलब्ध करा सकते हैं. मसलन एअर इंडिया को विदेशी मुद्रा में कर्ज देने के लिए शुरू में किसी भारतीय बैंक को नहीं बुलाया गया. घोष के विरोध करने पर स्टेट बैंक की पूछ हुई और उसके साथ करार हो भी गया. इसके बाद तो घोष ने यह सिद्ध करने की ठान ली है कि भारतीय बैंक किसी से पीछे नहीं हैं. स्टेट बैंक ने अमेरिका में आप्रवासी भारतीयों को निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान छेड़ रखा है जिसे सिटीबैंक ने भी अपने से बेहतर माना है. और पिछले पखवाड़े घोष ने आंकड़े प्रकाशित करके यह जता दिया कि उन्होंने अनेक ऐसे क्षेत्रों में विदेशी बैंकों को पछाड़ दिया है जिन पर उनका प्रभुत्व था.

नतीजतन टक्कर ले रहे विदेशी बैंकों पर कानून के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं. मसलन सीबीआई एक ऐसे बैंक के मामले की जांच कर रही है जिसने आप्रवासी भारतीयों से धंधे के चक्कर में विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन किया है. रिजर्व बैंक ने भी एक विदेशी बैंक की आप्रवासी भारतीयों से निवेश हासिल करने के लिए सामान्य ब्याज के अतिरिक्त कमीशन देने पर खिंचाई की थी.

दूसरी ओर विदेशी बैंकों के मुताबिक भेदभाव की वजह से वे निराशा भोग रहे हैं. आरोप है कि उन्हें तो साझा कोष स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई जबकि दो भारतीय बैंकों को इसके लिए हरी झंडी दे दी गई. शेयरों का लेन-देन करने वाली एक सहायक इकाई का उनका प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया, हालांकि बैंक प्रवक्ताओं के मुताबिक विदेशी बैंकों के विशेषज्ञ शेयर बाजार के व्यवसायीकरण में मदद दे सकते हैं. हाल ही में यह भेदभाव साफ जाहिर हुआ जब सरकार ने आप्रवासी भारतीयों के लिए शेयरों में निवेश केवल भारतीय बैंकों के जरिये करना अनिवार्य कर दिया. विदेशी बैंकों के कड़े विरोध की वजह से यह आदेश वापस लेना पड़ा. इससे जाहिर हुआ कि विदेशी बैंक अपने अंतरराष्ट्रीय तंत्र और आप्रवासी भारतीयों में अच्छी साख की वजह से उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं. विदेशी बैंक के एक अधिकारी कहते हैं, "अगर कोई विदेशी बैंक अच्छी सेवा उपलब्ध करा सकता है तो सरकार को किसका हित देखना चाहिए—भारतीय बैंक का या भारतीय ग्राहक का?"

लेकिन सरकार और भारतीय बैंक इस मसले को इस तरीके से नहीं आंकते. बहरहाल, विदेशी बैंक भारत के कुल बैंक व्यवसाय में अपनी भागीदारी में कोई नाटकीय इजाफे की उम्मीद नहीं करते पर उन्हें अपने लिए नियमों में छूट की गुंजाइश नजर आती है.

—टी.एन. नैनन और ब्यूरो रिपोर्ट

डीसीएम

पोत डूबने का खतरा

पिछले पांच वर्षों से डीसीएम झंझावातों से जूझ रही है लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि श्रीराम समूह के इस ध्वजपोत के डूबने का खतरा भी पैदा हो सकता है. हालांकि फिलहाल एकदम ऐसी घड़ी तो नहीं आ पहुंची है लेकिन ध्वजपोत को डूबने से बचाने के लिए उसका भार तो हल्का किया ही जा रहा है.

कभी लगता है कि निजी उद्योगों में पांचवें स्थान पर रह चुकी 530 करोड़ रु. वाली इस कंपनी के पतन का नया दौर शुरू हो चुका है. पिछले पखवाड़े इसने कोटा के अपने रासायनिक खाद कारखाने और दिल्ली की कपड़ा मिल को बेचने का विज्ञापन निकाला. कंपनी के पुनर्जीवन के लिए क्या बेचें और क्या न बेचें इस पर भी बहस जारी है.

कंपनी के अध्यक्ष बंसीधर शुरू में रासायनिक खाद कारखाना (जिसे वे खुद ही संभालते हैं) बेचने के लिए तैयार थे पर अब वे बिक्री के एकदम खिलाफ हैं. दरअसल इस साल के शुरू में बंसीधर के.के. बिड़ला के साथ बिक्री की बात तब तक चलाते रहे जब तक बिड़ला ने इसमें दिलचस्पी लेना बंद नहीं किया. तीन साल पहले तक डीसीएम के प्रबंध निदेशक रह चुके और अभी भी कंपनी के एक निदेशक चरत राम ने निदेशक मंडल को कोटा के कारखाने की बिक्री के खिलाफ तब कड़ा पत्र लिखा. उनका मानना था कि कंपनी की माली हालत को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 21 करोड़ रु. की जरूरत है जबकि 75 करोड़ रु. के करीब तो फालतू पड़ी जमीन, कुछ इमारतों और कंपनी के निष्क्रिय निवेश

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

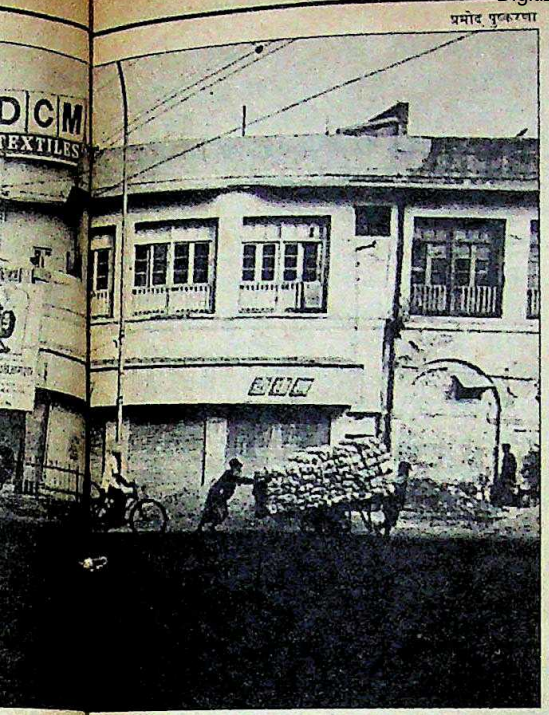

प्रमोद पुष्करणा

दिल्ली में डीसीएम की कपड़ा मिल

उधर बंसीधर ने एक बार फिर निदेशक मंडल को सुझाव दे डाला कि कंपनी को उबारने के लिए इसकी सभी इकाइयों को स्वतंत्र कर दिया जाए और परिवार के अलग-अलग सदस्य इनकी देखभाल करें. उनकी दलील है कि डीसीएम तो होल्डिंग कंपनी बनी रहे पर इसकी विभिन्न सहयोगी इकाइयां बना दी जाएं. इकाइयां स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज चलाएं. इसका साफ-सांफ मकसद यही है कि कलहग्रस्त श्रीराम परिवार के हरेक पूर्णकालिक निदेशक को अलग-अलग सहायक कंपनी सौंप दी जाए ताकि वे एक दूसरे के लिए बाधा न बन सकें.

करों के मद्देनजर सोचा जा रहा है कि एकदम नई कंपनियों का गठन किया जाए और डीसीएम का कारखाना और उपकरण उन्हें आठ साल के लिए पट्टे पर दे दिए जाएं. बाद में उन्हें बेच दिया जाए.

बहरहाल कंपनी के पुनर्गठन पर विचार की प्रक्रिया कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद ही शुरू हो सकेगी. लेकिन वित्तीय संस्थाओं का कहना है कि इसके लिए विस्तृत योजना पर विचार किया जाना चाहिए ताकि उसे दिसंबर में होने वाली अंशधारियों की सालाना आम सभा में पेश किया जा सके.

उधर दिल्ली की कपड़ा मिल की जमीन विकसित करने और बेचने के डीसीएम के प्रस्ताव पर अदालत में मामला चलने के कारण पूरी योजना ही पचड़े में फंस गई है. इस मुकदमे का जल्दी ही फैसला होने वाला है. माना जा रहा है कि मंजूरी मिल जाने पर जमीन बिक्री की परियोजना से काफी रकम हासिल होगी. तब यह रकम डीसीएम की सेहत सुधारने पर खर्च की जा सकेगी. लेकिन चरत राम इस योजना को लेकर भी आशंकित हैं. उनका मानना है कि जमीन विकसित करने में काफी नकदी लगेगी और जितनी दरकार है उतनी रकम कंपनी के पास नहीं है.

इन मसलों पर अंतिम फैसला अगले महीने के शुरू में होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में ही हो पाएगा. मंडल को दिल्ली की जमीन के बारे में अदालती फैसले के संदर्भ में निर्णय लेना पड़ेगा, साथ ही खाद कारखाने और कपड़ा मिल की खरीदी के लिए आए प्रस्तावों पर भी गौर करना पड़ेगा.

इस बीच चरत राम ने श्रीराम घराने की होल्डिंग कंपनी 'मदन मोहन लाल श्रीराम ऐंड कंपनी' के निदेशकों को भेजी अपनी तीखी टिप्पणी में लिखा है कि 25 साल पहले से इस होल्डिंग कंपनी द्वारा संचालित 11 कंपनियों में से 8 या तो बंद हो चुकी हैं या दूसरे प्रबंधकों के पास चली गई हैं. इसी तरह कंपनी की 20 अचल संपत्तियों में से 11 बेची जा चुकी हैं और यह भी कि "पिछले 25 वर्षों से निदेशक/अंशधारी इन व्यवसायों/संपत्तियों को बेचकर ही अपना भरण-पोषण कर रहे हैं." हालत खस्ता होने के लंबे सिलसिले की ओर संकेत करते हुए चरत राम ने सवाल किया है, "इस रफ्तार से और कितने वर्षों तक हम जी सकेंगे?"

जहां तक खुद डीसीएम कंपनी का सवाल है तो इसके कर्ताधर्ता एकदम विपरीत ध्रुवों पर हैं. साथ ही कंपनी के सामने नकदी का भी बड़ा संकट मुंह बाये खड़ा है. कपड़ा उद्योग का आलम यह है कि कंपनी के पास धागा खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं. यहां तक कि सालाना बीमा प्रीमियम देने में भी कठिनाई पेश आ रही है. एक या दो इकाइयों की बिक्री से दूसरी कठिनाई का समाधान तो निकल आएगा लेकिन यह स्थायी नहीं होगा. जब तक इसके कर्ताधर्ताओं के मतभेद खत्म नहीं होते तब तक कंपनी भंवर की ओर बढ़ती रहेगी.

—टी.एन. नैनन

को बेचने से मिल जाएंगे.

उस दरम्यान श्रीराम परिवार के कुछ युवा सदस्य ओसवाल एग्रो मिल्स के अभय ओसवाल से न सिर्फ रासायनिक खाद कारखाना बल्कि कोटा स्थित कुछ और इकाइयां मसलन घाटे में चल रहा सीमेंट कारखाना और एक रासायनिक कांप्लेक्स बेचने की भी बात चला रहे थे. ओसवाल 125 करोड़ रु. तक देने को तैयार थे. ऐसा होने पर डीसीएम के पास देनदारियां चुकाने के बाद 65 करोड़ रु. के करीब बच जाते.

लेकिन जब ओसवाल के साथ बातचीत पटने लगी तभी पूरे निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष वित्तीय संस्थानों (जिनके पास डीसीएम के 42 फीसदी शेयर हैं) के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि संपत्ति की हर तरह की बिक्री सिर्फ खुले विज्ञापनों के ही मार्फत होनी चाहिए. इस बीच चरत राम डीसीएम-टोयोटा और श्रीराम फाइबर्स के शेयरों में लगी डीसीएम की 'निष्क्रिय पूंजी' बेचने के पक्ष में हैं. इन दोनों का प्रबंध भरत राम के बेटों के हाथ में है. वैसे डीसीएम के निदेशक मंडल की पिछली बैठक में चरत राम ने घोषणा की थी कि सभी फैसले 'श्रीराम घराने के हितों के मद्देनजर किए जाएंगे न कि अंशधारियों के हित में'. लगता है यह टिप्पणी ज्यादा असरदार नहीं हुई.

श्रीराम समूह के कर्ताधर्ता एकदम विपरीत ध्रुवों पर हैं. नकदी का संकट टालने के लिए क्या बेचें, क्या न बचें इस पर समूह के भीतर बहस जारी है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एअर इंडिया

मुश्किल में फंसे महाराजा

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक में तनातनी चरम सीमा पर

पिछले दो वर्षों में एअर इंडिया के निदेशक मंडल में चलने वाली लड़ाई ने सार्वजनिक विवाद का रूप ले लिया और सार्वजनिक क्षेत्र के निदेशक मडलों के निजीकरण का सरकार का साहसिक प्रयोग डावांडोल होने लगा. अध्यक्ष रतन टाटा और प्रबंध निदेशक राजन जेतली के बीच की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई. पिछली मई में एक समय ऐसा आया कि समूचे निदेशक मंडल ने 30 जून को अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले ही इस्तीफे की धमकी दे डाली. बोर्ड के एक सदस्य, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के प्राचार्य धरणी सिन्हा ने तो जेतली की शैली की खुलेआम आलोचना की. अब यह छिपी हुई बात नहीं कि टाटा और जेतली के बीच कड़ी चिट्ठियों का आदान-प्रदान हुआ था और टाटा ने इन पत्रों की प्रतिलिपियां प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी थीं.

लेकिन पिछले पखवाड़े केंद्र सरकार ने एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के निदेशक मंडलों का कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद नए निदेशकों के नामों की घोषणा कर दी. दोनों मंडलों के सदस्यों की संख्या 15-15 कर दी गई है और दोनों ही मंडलों में गैर-सरकारी सदस्य बहुमत में हैं. लेकिन टाटा और जेतली के रिश्ते कैसे सुधारे जाएंगे और दोनों में अंततः किसका हाथ ऊपर रहेगा, यह सवाल बना ही हुआ है.

कम-से-कम एक मौके पर तो जीत जेतली की हुई. धरणी सिन्हा और रेडिफ्यूजन विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख अरुण नंदा की छुट्टी कर दी गई. नंदा भी एअरलाइन प्रबंधन के कामकाज पर कड़ी निगाह रखते रहे हैं. एअर इंडिया के निदेशक मंडल में सिर्फ एक गैर-सरकारी सदस्य—उद्योगपति विवेक भरत राम को ही बरकरार रखा गया है. जेतली के एकमात्र समर्थक सिर्फ यही थे, बाकी लोग बमुश्किल 22 महीने

अध्यक्ष रतन टाटा को लगता है कि निदेशक मंडल सरकार के प्रति जवाबदेह है इसलिए उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि प्रबंधन तयशुदा लक्ष्य क्यों नहीं पा सका

निदेशक मंडल में रहे.

लेकिन नए नामों को देखकर यही संकेत मिलता है कि सरकार निदेशक मंडलों में सक्रिय निदेशकों को रखने का प्रयोग जारी रखेगी. एअर इंडिया के निदेशक मंडल में शामिल किए गए नए निदेशक हैं—मरक्यूरी ट्रेवल्स के अध्यक्ष और ईस्ट इंडिया होटल्स के निदेशकों में से एक गौतम खन्ना, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और एअरफेट के अध्यक्ष साइरस गजदर, व्यापारिक संघ कंफेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के महानिदेशक तरुणदास, एनपीसीसी के जे.के. मेहरा और फ्रांस में राजदूत रहे एअर चीफ मार्शल (रिटायर) इदरीस हसन लतीफ की पत्नी बिल्कीस लतीफ.

इंडियन एअरलाइंस के नए निदेशक हैं—ताज होटल समूह के अजीत केरकर, मद्रास के उद्योगपति सुरेश कृष्ण, पैसिफिक एरिया ट्रेवल के अवैतनिक सचिव कृष्ण अमला, हिंदुस्तान टाइम्स की शोभना भरतिया और फिल्म अभिनेत्री शर्मीला टैगोर. वायुदूत के प्रबंध निदेशक हर्ष वर्धन को भी इंडियन एअरलाइंस के निदेशक मंडल में रखा गया और पर्यटन महानिदेशक बी.के. गोस्वामी को दोनों एअरलाइनों के निदेशक मंडलों में नियुक्त किया गया.

टाटा और बिड़ला दोनों को यह एक तरह की चेतावनी है कि वे अपने मतभेद भुलाकर खराब छवि वाली एअरलाइन में रुचि लें. जैसा कि एक अधिकारी ने कहा, "टाटा को भले ही कंपनी का नहीं वरन निदेशक मंडल का अध्यक्ष माना जाए, जेतली से उम्मीद की जाती है कि वे अपने सभी फैसले निदेशक मंडल से मंजूर करवाएं." नागर विमानन मंत्रालय के सूत्र इस सिलसिले में इंडियन एअरलाइंस की मिसाल देते हैं कि किस तरह उद्योगपति राहुल बजाज की अध्यक्षता और प्रबंध निदेशक गैरी पायस के नेतृत्व में उसके निदेशक मंडल ने सहजता से काम किया. दरअसल इसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि इंडियन एअरलाइंस अभी भी खूब मुनाफा दे रही है. एअरलाइन को 1987-88 में 75 करोड़ रु. का रिकार्ड मुनाफा हुआ. बजाज को अब एअर इंडिया के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है—शायद इस उम्मीद में कि वे टाटा और जेतली के झगड़े को काबू में रखेंगे.

लेकिन टाटा और जेतली का झगड़ा सुलझाना इतना आसान नहीं होगा. जेतली द्वारा पिछले साल के शुरू में प्रबंध निदेशक का पदभार संभालने के तुरंत बाद ही तनातनी शुरू हो गई थी. एअर इंडिया के चालक दलों ने जब हड़ताल की थी तो निदेशक मंडल चाहता था कि

CC-0. In Public Domain. Panini K

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. इसके बावजूद जेतली ने चालक दलों से समझौता कर लिया. उसके बाद से तो दोनों के संबंध बदतर होते चले गए. पिछले नवंबर में यह तनातनी उस वक्त चरम सीमा पर पहुंच गई जब निदेशक मंडल को मालूम पड़ा कि 24 करोड़ रु. के अनुमानित मुनाफे के बावजूद एअर इंडिया को 1987-88 में भारी नुकसान होने जा रहा है. यह आंकड़ा 43.41 करोड़ रु. है.

इस पर जेतली का कहना था कि मुनाफे की चिंता की वजह से एअर इंडिया की स्थिति पिछले 15 साल से पूर्ववत है. वह न तो अपने विमानों के बेड़े का विस्तार कर रहा है और न ही नए रूट तलाश रहा है.

लेकिन निदेशक मंडल में चलने वाले नाटक से जो बड़ा मुद्दा उभरा, वह निदेशक मंडल की भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित है. टाटा और निदेशक मंडल के दूसरे सदस्यों को लगता रहा है कि चूंकि वे सरकार के प्रति जवाबदेह हैं इसलिए उन्हें यह जानने का पूरा हक है कि प्रबंधन अपने ही तय किए लक्ष्यों को हासिल क्यों नहीं कर सका. दरअसल सिन्हा का ख्याल था कि निदेशक मंडल को प्रबंधन के कामकाज पर और कड़ी निगाह रखनी चाहिए. पिछले निदेशक मंडल की आखिरी बैठक के बाद भी उन्होंने अपनी इस धारणा के पक्ष में कहा था, "निदेशक मंडल को जब मालूम पड़ा कि एअरलाइन डूब रही है, तभी उसने उसे मार्गनिर्देश देने की कोशिश की."

जेतली ने निदेशक मंडल की माहवारी बैठकों में एअरलाइन के प्रबंधन की बारीकी से छानबीन किए जाने पर तीव्र रोष जताया. उनका मानना था कि निदेशक मंडल को अपनी नीति-निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए. और प्रबंधन को सरकार के साथ तालमेल बिठाने में मदद भर करनी चाहिए.

लेकिन निदेशक मंडल अपनी अंतिम बैठक तक इन विचारों को मानने को तैयार नहीं था. उसका जोर इस बात पर था कि प्रबंधन को सेवाओं में सुधार लाने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ एअरलाइन को फायदेमंद बनाने की एक सर्वांगीण योजना तैयार करनी चाहिए. इससे न केवल नए विमानों (बेड़े के विस्तार के लिए एक सात वर्षीय योजना अभी हाल ही में तैयार हुई है) की खरीदारी रुक गई बल्कि 1988-89 के बजट को मंजूरी भी नहीं मिली.

लेकिन जहां तक टाटा का सवाल है, निदेशक मंडल की सक्रिय भूमिका की उनकी धारणा जस की तस है. वे कहते हैं, "मुझे लगता है कि निदेशक मंडल शेयर धारकों (इस मामले में सरकार) का ट्रस्टी है. लिहाजा फायदेमंद निवेश के बारे में निर्देश की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है. यदि सरकार सिर्फ नाममात्र का ही निदेशक मंडल चाहती है तो हमें क्यों परेशान करती है? इसके लिए तो सरकारी अधिकारियों का निदेशक मंडल बना देना ही काफी होगा."

टाटा को लगता है कि विमान ईंधन की ऊंची कीमत जैसे मुद्दे नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष रखे जाने चाहिएं, निदेशक मंडल के नहीं. निदेशकों को तो एअर इंडिया के समूचे कामकाज पर नजर रखनी पड़ती है. दरअसल निदेशक मंडल के सदस्यों ने अपने कामकाज को गंभीरता से लिया. यही वजह थी कि वे शुरू में विवेक भरत राम के इस सुझाव पर रजामंद हो गए कि मंडल की हर महीने बैठक होनी चाहिए. इस कार्रवाई के लिए अध्यक्ष की खासी आलोचना हुई थी.

निदेशक मंडल के नए गैर-सरकारी सदस्य एअर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के इन विपरीत ध्रुवों वाले विचारों पर कैसा रुख अपनाएंगे यह पहली कुछ बैठकों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. बजाज की मौजूदगी महत्वपूर्ण साबित होगी. मुख्य अधिकारी के रूप में कामकाज के अपने बढ़िया रिकार्ड के कारण और अब इंडियन एअरलाइंस के अध्यक्ष के बतौर बजाज निदेशक मंडल को और मजबूत ही बनाएंगे.

लेकिन सिर्फ एक साल के लिए एअर इंडिया के नए निदेशक मंडल को नियुक्त करके सरकार ने जाहिर कर दिया है कि वह अभी और इंतजार के मूड में है. बताया जाता है कि नागर विमानन मंत्रालय विमान ईंधन की कीमत को तर्कसंगत बनाने पर सहमत हो गया है और संभव है कि महाराष्ट्र सरकार भी ईंधन पर लगाया गया अधिभार वापस ले ले. ऐसे में प्रबंधन पर एअर इंडिया को मुश्किलों से उबारने का दबाव स्वतः ही बढ़ जाएगा. बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि निदेशक मंडल और प्रबंधन मिल-जुलकर काम कर सकते हैं या नहीं. लेकिन पिछले निदेशक मंडल के अनुभव को देखते हुए यही लगता है कि एअरलाइन को आगे आने वाली परेशानियां टालने में मुश्किल होगी.

—एम. रहमान और
सलिल त्रिपाठी
ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

प्रबंध निदेशक राजन जेतली का मानना है कि निदेशक मंडल को एअरलाइन चलाने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ नीतिगत मामलों तक सीमित रहना चाहिए

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Haridwar.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उर्वरक कारखाने

पांव पसारने का पराक्रम

महज एक उत्पाद वाली छवि तोड़ने की कोशिश

उर्वरक कारखाने का नाम लेते ही जिस चीज की छवि आंखों के आगे उभरती है, वह है किसानों के लिए बदबूदार उत्पाद तैयार करती भारी-भरकम औद्योगिक इकाइयों की, जिनके उत्पादों की बिक्री संयोग पर ही निर्भर हुआ करती थी.

लेकिन अब इनकी 'महज एक उत्पाद' से जुड़ी पुरानी छवि तेजी से बदल रही है. ढेर सारी पूंजी के साथ ये कंपनियां अब जोर-शोर से कई उत्पाद तैयार करने वाली विशालकाय कंपनियों के रूप में उभर रही हैं. 'बहुउत्पाद' के इस जुनून में उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं वे अनोखी ही नहीं, बेतुकी भी हैं. उदाहरण के तौर पर:

- देश की सबसे बड़ी खाद कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स ऐंड फर्टिलाइजर (आरसीएफ) अब अखबारी कागज, सिंथेटिक रबर और शायद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनाएगी. संभावित पूंजी निवेश: 600 करोड़ रु.
- सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज (एसपीआईसी) पेट्रोरसायन, दवाओं, रसायनों और जहाजरानी में पूंजी लगाएगी. अनुमानित पूंजी: 350 करोड़ रु.
- जुआरी एग्रो केमिकल्स सीमेंट, दूरसंचार, गृहनिर्माण और खाद्य परिष्करण में उतरने को कटिबद्ध है. अनुमानित पूंजी: 250 करोड रु.
- गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी (जीएनवीएफसी) तो दुपहिया वाहन निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर ही चुकी है. अब वह रसायनों, पेट्रोरसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है. अनुमानित पूंजी: 350 करोड़ रु.
- गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी (जीएसएफसी) की योजना रसायन, पेट्रोरसायन और प्लास्टिक के क्षेत्र में प्रवेश करने की है. अनुमानित पूंजी: 650 करोड़ रु.
- भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था (इफको) और कृषक भारती कोऑपरेटिव (कृभको) के बीच पेट्रोरसायन क्षेत्र में उतरने की कड़ी स्पर्धा चल रही है. अनुमानित पूंजी: 1200 करोड़ रुपए.

खाद बनाने वाली छोटी इकाइयां भी बड़ी कंपनियों का अनुकरण कर सकती हैं. इनमें से कई तो बहुउत्पादक हो भी गई हैं. खाद कंपनियों में शायद ही कोई अपवाद हो वरना ज्यादातर तो भविष्य की योजनाएं नए सिरे से बना रही हैं. सूखे के कारण खाद की बिक्री तेजी से गिरी है. नतीजतन खाद कंपनियों की हालत खस्ता हो गई है.

पिछले साल जमा स्टॉक बढ़ गया, कीमतें कम करने के लिए कंपनियों में होड़ मची और लाभ की मात्रा घट गई. मिसाल के तौर पर प्रमुख खाद कंपनियों का कर पूर्व लाभ 1985-86 के 91 करोड़ रु. के मुकाबले 1986-87 में 24 करोड़ रु. ही रह गया. 1987-88 में भी राहत नहीं मिली. अब हालांकि इंद्र देवता मेहरबान हो चले हैं पर कोई भी दोबारा जोखिम लेने को तैयार नहीं.

दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करना स्वाभाविक प्रक्रिया होने के बावजूद यह सिक्के का एक ही पहलू है. खाद कंपनियों के प्रबंधकों के संघर्ष भरे अनुभव के बावजूद इनमें से अधिकांश के लिए उत्पादन की विभिन्नता एक शगल ही है, बावजूद इसके कि इस नई प्रवृत्ति को 'पूंजी के पुनर्निवेश' और 'नए उत्पादन चक्र' जैसे सुंदर सिद्धांतों का जामा पहना दिया गया है. नतीजा यह निकला है कि दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कंपनियों में कुछ ही ऐसी हैं जो विवेक से काम ले रही हैं.

कैप्रोलेक्टम, नाइलन, मेलामाइन और आटगन गैस के क्षेत्र में कदम रखने वाली है. जीएसएफसी के वित्तीय सलाहकार एच.एन. इलाविया कहते हैं, "दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करने के मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा संबद्ध क्षेत्रों में ही कदम रखा है." फर्टिलाइजर ऐंड केमिकल्स ट्रावनकोर (फैक्ट) भी इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कैप्रोलेक्टम के क्षेत्र में उतर रही है.

लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जीएनवीएफसी जैसी कंपनी द्वारा चाहे जिस क्षेत्र में पांव पसारने की बात तर्कसंगत नहीं लगती. इस कंपनी ने बीमार स्कूटर कारखाना हाथ में लेने के अलावा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की इकाइयां शुरू की और केमिकल्स में भी पांव पसारे. जीएनवीएफसी के प्रबंध निदेशक के.जी. रामनाथन बताते हैं, "अब खाद उद्योग से किसी लाभ की उम्मीद नहीं रह गई है." लेकिन दुपहिया गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का क्षेत्र बेहद प्रतियोगिता भरा है.

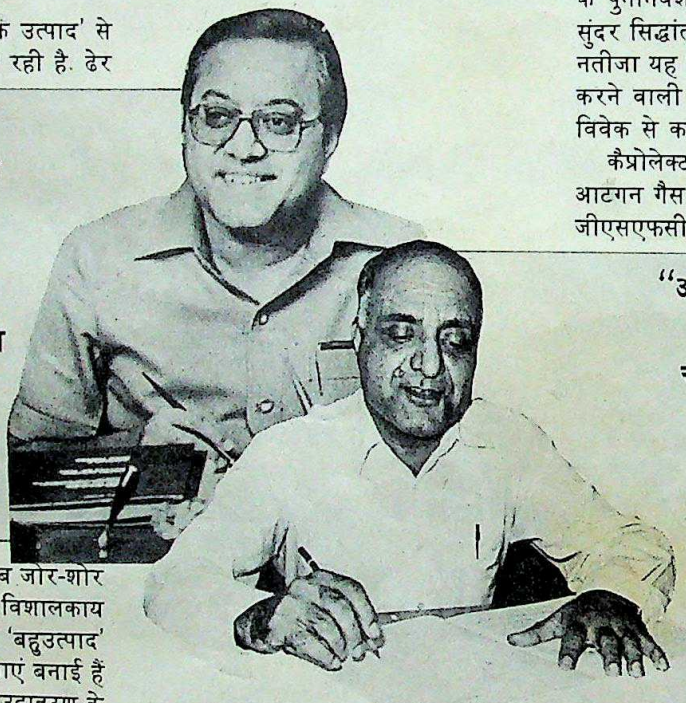

"विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को छोड़ हमारी नई परियोजनाएं खाद्य परिष्करण से संबंधित हैं. अभी हम कच्चे माल के थोक आपूर्तिकर्ता हैं"

ए.सी. मुथिया
उपाध्यक्ष, एसपीआईसी

"आपके पास केवल प्रबंध क्षमता होनी चाहिए. अगर आप एक धंधा ठीक चला सकते हों तो सभी धंधे अच्छी तरह से चला सकते हैं"

एच.एस. बावा
उपाध्यक्ष, अरावली फर्टिलाइजर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऐसे में अगर विपणन का तंत्र मजबूत न हुआ तो इस तरह उत्पादन के दूसरे क्षेत्र में जाने का फैसला महंगा पड़ सकता है.

लेकिन अरावली फर्टिलाइजर्स के उपाध्यक्ष और खाद्य परिष्करण सरीखे उद्योग में हाथ आजमाने वाली जुआरी के अध्यक्ष एच.एस. बावा इससे एकदम असहमत हैं. वे कहते हैं, "आपके पास केवल प्रबंध क्षमता होनी चाहिए. यदि आप एक धंधा अच्छी तरह चला सकते हैं तो आप सभी धंधों को ठीक तरह चला सकते हैं."

मद्रास की एसपीआईसी की भी यही धारणा है. इसके उपाध्यक्ष ए.सी. मुथिया कहते हैं, "विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को छोड़कर हमारी सारी नई परियोजनाएं खाद्य परिष्करण से संबंधित हैं. अब भी हम कच्चे माल के एकमात्र थोक आपूर्तिकर्ता हैं." इस तरह सतर्क खाद कंपनियां विस्तार के लिए समान तकनीक वाले उद्योगों की तलाश कर रही हैं.

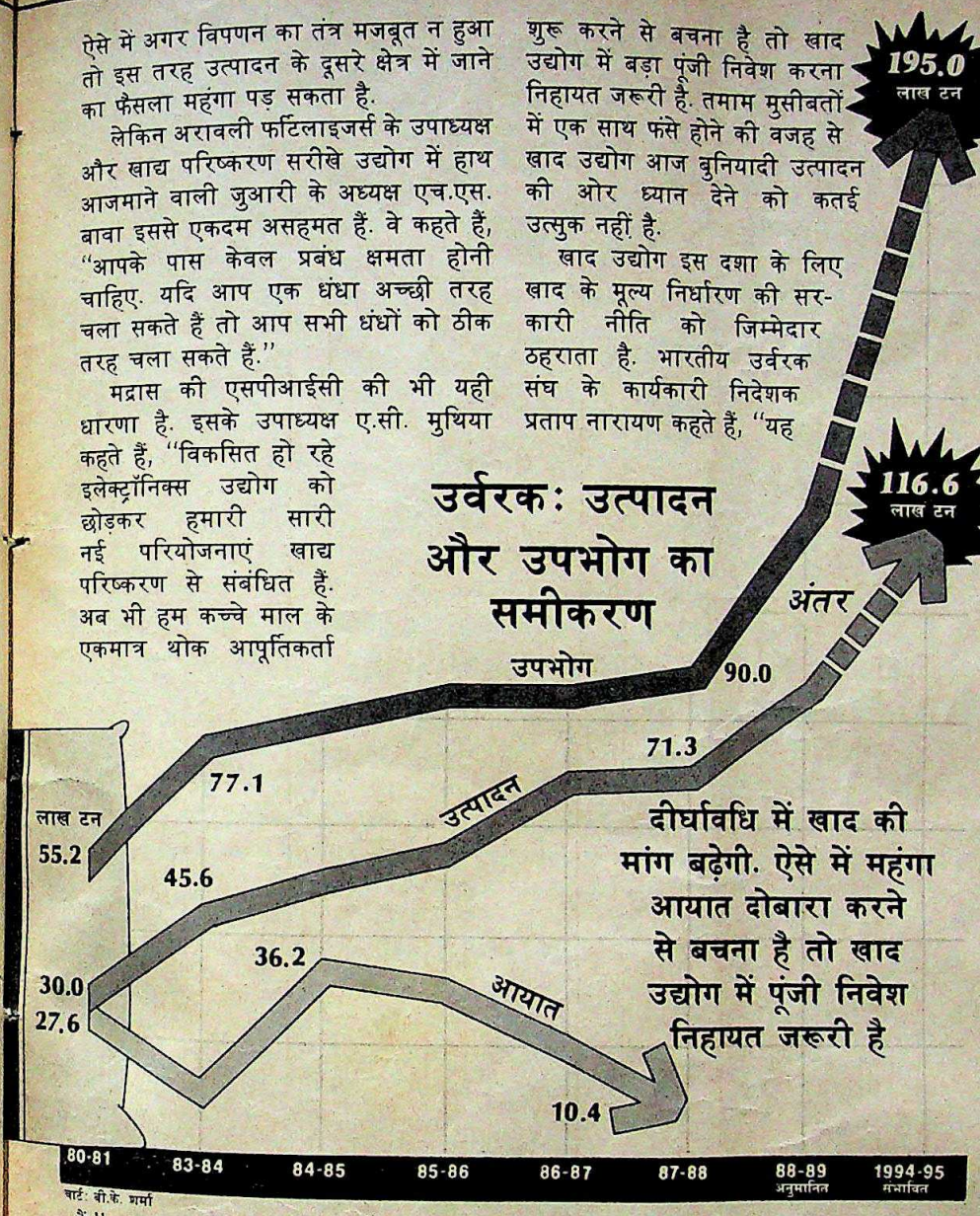

खाद कंपनियों की चिंता की वजहें और भी हैं. अभी तक खाद उद्योग की विस्तार की दृष्टि से काफी अहमियत थी. सरकार की मूल्य निर्धारण की नीति की वजह से कोई भी खाद उत्पादक इकाई 12 फीसदी लाभ की दर से अपनी क्षमता का 80 फीसदी तक का स्तर हासिल कर सकती थी. अचानक हालात ने पलटा खाया और इस उद्योग को बड़े पैमाने पर विस्तार की योजनाएं बनाने पर मजबूर होना पड़ा.

यह तय है कि दीर्घावधि में खाद की मांग बढ़ेगी और ऐसे में यदि महंगा आयात दोबारा शुरू करने से बचना है तो खाद उद्योग में बड़ा पूंजी निवेश करना निहायत जरूरी है. तमाम मुसीबतों में एक साथ फंसे होने की वजह से खाद उद्योग आज बुनियादी उत्पादन की ओर ध्यान देने को कतई उत्सुक नहीं है.

खाद उद्योग इस दशा के लिए खाद के मूल्य निर्धारण की सरकारी नीति को जिम्मेदार ठहराता है. भारतीय उर्वरक संघ के कार्यकारी निदेशक प्रताप नारायण कहते हैं, "यह सचमुच बड़े अफसोस की बात है कि खाद कंपनियां अपने से इतर उद्योगों में विस्तार कर रही हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब हरेक खाद कंपनी सिर्फ अपने ही धंधे में विस्तार करना चाहती थी. खाद कंपनियों में फैली घबराहट के लिए अनिश्चित नीतियां ही कारणीभूत हो सकती हैं."

खाद उद्योग का विश्वास डिगाने में सरकार के विरोधाभासी रुख का बड़ा योगदान है. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में सुधार (आज 80 फीसदी) आने के बावजूद भारी आयात और पिछले साल उसे बाजार में जारी कर दिए जाने की वजह से सरकार के कम आयात के आश्वासन पर से कंपनियों का भरोसा हट गया है.

इसके अलावा नीतियों में और भी बड़ा फेरबदल होगा, इसमें भी किसी को शक नहीं है. खाद पर दी जाने वाली सबसिडी की रकम 1988-89 में 3000 करोड़ रु. तक पहुंच जाएगी. ऐसे में सरकार इस गैर योजना व्यय में कटौती करने को प्रवृत्त हो सकती है. साथ ही उर्वरक इकाइयों के लाभ की दर 11 फीसदी के आसपास तक घटा देने की और उत्पादन क्षमता 85 फीसदी तक बढ़ाने की बात भी चल रही है. नारायण की नाराजगी ठीक इसी को लेकर है.

लेकिन सरकार मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं. केंद्रीय उर्वरक सचिव के.डी. वासुदेव कहते हैं, "खाद कंपनियां सूखे से डर कर और क्षेत्रों में जा रही हैं. मुझे लगता है कि खाद कंपनियों के कुछ अंदेशे तो बिलकुल निराधार हैं. यह सही है कि नीतियां लचीली होनी चाहिए. लेकिन उर्वरक उद्योग को भरोसे में लिए बगैर कुछ भी नहीं किया जाएगा." समस्या महज इतनी है कि भविष्य में उद्योग की भूमिका को लेकर उसे विश्वास में नहीं लिया गया. मसलन उर्वरक उद्योग के लिए अगले पांच वर्षीय योजनाकाल में आधारभूत साबित होने वाली वरदराजन समिति की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 'या तो (खाद का) उत्पादन देश में ही हो या बाहर से खरीद की जाए.' उद्योग ने इसका अर्थ भविष्य में उर्वरकों के उन्मुक्त आयात से लगाया है. हालांकि योजना बनाने वाले अब भी आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कहते हैं लेकिन सरकार की पशोपेश साफ नजर आती है.

वैसे स्थिरता के लिए कुछ सीमा तक विस्तार भी जरूरी है. भारतीय खाद उद्योग के संबंध में विश्व बैंक के एक ताजा अध्ययन में कहा गया है कि खाद योजनाओं में भारतीय निवेशकों के डर की वजह इसकी कीमतों में आने वाला उतार-चढ़ाव है. लेकिन यहां असली सवाल यह है कि क्या बिना सोचे-विचारे किए गए विस्तार से कोई मकसद हासिल होगा.

संभव है कि दूसरे क्षेत्रों में पांव पसारने की प्रवृत्ति इस उद्योग के लिए फलदायी साबित हो, या संभव है फलदायी न हो, परंतु एक बात तय है कि विस्तार का तूफान गुजरने के बाद उर्वरक उद्योग अपनी पहले जैसी अवस्था में नहीं रह जाएगा.

—आनंद पी. रमन, ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी टी इस्पात इंडो, इंडोनेशिया
निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड
इस्पात एल्वायज लिमिटेड

और अब

इस्पात प्रोफाइल्स इंडिया लिमिटेड

इस्पात

साझा हमनाम
इस्पात इरादे

'हमारे पास तकनीकी ज्ञान है और हैं बेहतर उपलब्ध सुविधाएं. लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा महान प्रतियोगी उत्कर्ष हैं हमारे इरादे. इनसे हमने न सिर्फ तेजी से प्रगति करने में ही सफलता पायी है, बल्कि इसने हमें अपने ग्राहकों और शेयरहोल्डरों को संतुष्ट करने के लिए, मजबूत इरादे और उत्साह दिया. ये इरादे हमारे भविष्य के विकास में सहायक होंगे.'

उत्पादन प्रारंभ हो चुका है
आपके निवेश पर पहले दिन से ही लाभ

★ अग्रणी प्रवर्तक— भारत तथा विदेश में इस्पात तथा संबद्ध उद्योगों में विस्तृत अनुभव. इसके पूर्व हम पी टी इस्पात इंडो, निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड (एन डी आइ एल) तथा इस्पात एल्वायज लिमिटेड (आइ ए एल) जैसी सफल कंपनियों का प्रवर्तन कर चुके हैं

★ प्रवर्तकों का लक्ष्य रहा है शेयर होल्डरों को लाभ देना— एन डी आइ एल और आइ ए एल के शेयरों में प्रचलन के पहले साल से ही अच्छी प्रशंसा और रिटर्न मिला.

★ और अब इस्पात प्रोफाइल्स – इटली की डैनीएली की तकनीक पर आधारित विश्व के परिष्कृत और किफायती स्टील मिल कांप्लेक्स में से एक.

★ 144 करोड़ रुपये की सूक्ष्म-परिष्कृत परियोजना-नियत समय से पहले जिसने काम करना शुरू कर दिया है.

★ उच्च मूल्य संवर्द्धित उत्पाद संभार-रेल्स, एच-बीम्स, स्क्रूरल्स, स्टेनलेस स्टील सेक्शंस, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद तथा इसकी तदनुरूप रूपरेखा इसके महान योगदान के प्रति आश्वस्त करती है.

★ आयात का विकल्प बनने के लिए एच – बीम्स और रेल्स का उत्पादन.

★ भारी कीमत के आर्डर कंपनी को मिल चुके हैं.

★ 'कोर सेक्टर' के उद्योगों जैसे रेलवे, विद्युत, तेल उत्खनन, सुरक्षा, निर्माण, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग आदि में इसके उत्पादों का प्रयोग शुरू.

★ 80 सी सी तथा अन्य टैक्स लाभ

★ अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली तथा पुणे के स्टाक एक्सचेंजों में सूचिबद्ध

☐ भारत का निजी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा संयत्र जो रेल्स बनाता है.
☐ भारत का पहला यूनिवर्सल मिल जो एच-बीम्स बनाता है.

प्रत्येक 10 रुपये या सम मूल्य के
2,15,70,000 के इक्विटी शेयर जारी
इश्यू खुलने की तारीख :
नान रेजीडेंट भारतीयों के लिए : 6 अगस्त 1988
भारतीय जनता के लिए : 9 अगस्त 1988

इस्पात प्रोफाइल्स इंडिया लिमिटेड
पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016
फैक्स : 91 33 297396, फोन नं. 29-4395 / 4314
टेलेक्स : 021-2897 / 2810, कारखाना :- सनसवादी
तालुका : शिरूर, जिला : पुणे (महाराष्ट्र).

इश्यू के मैनेजर्स

एस बी आइ कैपिटल मार्केट्स लि.
ग्रिंडलेज बैंक पी एल सी
मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन

द इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन

जे. एम. फाइनैंसियल ऐंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टैंसी सर्विसेज प्रा. लि.

इंडस्ट्रियल फाइनांस कारपोरेशन ऑफ इंडिया
मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन

बैंक ऑफ इंडिया
मर्चेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट

इश्यू के सलाहकार

इंडियन बैंक
मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन

कंप्यूटेक इंटरनेशनल लि.
कलकत्ता

ISPAT PROFILES. Changing the profile of Steel

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

PRESSMAN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

फिर से मायूसी

पर निराशा अस्थायी है

पिछले पखवाड़े लगा कि शेयर बाजार परंपरागत निराशा के गर्त से उबरने लायक ही नहीं रह गया है. यह खबर पहुंचते ही कि नारायणदत्त तिवारी अब नॉर्थ ब्लॉक की शोभा नहीं बढ़ाएंगे, कुछ दिनों पहले का उत्साह भरा माहौल मायूसी में तब्दील हो गया. हालांकि उनकी जगह आए शंकरराव चव्हाण ने बाजार में आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना के लिए कुछ उत्साहवर्धक बातें तो जरूर कहीं पर शेयरों की कीमतें लगातार गिरती चली गईं.

एक समस्या यह भी थी कि लाभांश से होने वाली आमदनी पर टैक्स की छूट मिलने की संभावना दूर की कौड़ी हो गई. पर असल मंदी इस प्रस्ताव से आई कि दलालों और फुटकर धंधा करने वालों को अपनी रोजाना बिक्री पर टैक्स अदा करना पड़ेगा. हालांकि कहा गया था कि प्रस्तावित

चार्ट: बी.के. शर्मा

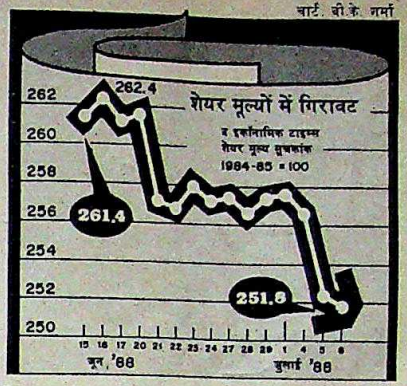

टैक्स की रकम प्रतिभूतियां और विनिमय नियंत्रण बोर्ड का कोष समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी. बावजूद इसके, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. प्रस्तावित टैक्स के विरोध में एक दिन के लिए व्यापार का बहिष्कार हुआ. नतीजतन बाजार की अनिश्चितता में और इजाफा हो गया. आखिरकार बंबई शेयर बाजार के अधिकारियों ने तेजड़ियों पर खासा पड़ता थोप देने का फैसला किया और इस तरह पिछले महीने की वसूली पर अंकुश लग गया.

नतीजतन पिछले पखवाड़े इकॉनॉमिक टाइम्स का शेयर मूल्य सूचकांक 261.4 से लुढ़ककर 251.8 पर पहुंच गया. बाजार की अगुआई करने वाला रिलायंस भी नीचे गिर गया तथा टाटा स्टील और टेल्को दोनों ही मैदान छोड़ते दिखाई दिए.

शेयरों ने इसके बाद और डुबकी नहीं खाई तो उसकी एक वजह यह थी कि बाजार में कुछ हद तक आत्मविश्वास लौट आया था क्योंकि मानसून अच्छी उम्मीदें बंधा रहा था. यानी इस साल उद्योगों का कामकाज बेहतर ही रहेगा. इन खबरों के मद्देनजर कि नीतियां अभी और उदार की जाएंगी, एमआरटीपी की सीमा में आने वाली कंपनियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं.

साथ ही इस दौरान ज्यादातर कंपनियों के कामकाज में भी सुधार हुआ. बेहतर बिक्री और मुनाफे के चलते ग्रेसिम जैसी कुछ कंपनियों ने लाभांश बढ़ाने और बोनस शेयर देने की घोषणा की. यहां तक कि बांबे डाइंग (जिसका मुनाफा कम होने का अंदेशा था) भी ऊपर चढ़ गया. पर इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि जून में बाजार में आया उफान फना हो गया है. लेकिन बाजार की मूल प्रवृत्ति शेयरों की कीमतों में तेजी के हक में है. ऐसे में अगला पखवाड़ा अहम साबित हो सकता है.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	नीचा	बंद 6.7.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	40.00	30.25	38.00	0.50 +
एसोसिएटेड सीमेंट	265.50	128.50	212.00	1.00 +
एटलस कोप्को	63.50	33.50	46.00	1.00 —
एशियन पेंट्स	175.00	128.75	150.00	2.50 —
बजाज ऑटो	520.00	187.50	231.25	11.25 —
बड़ौदा रेयॉन	282.50	140.00	235.00	12.50 +
बाटा इंडिया	77.25	50.50	69.50	3.25 —
भारत फोर्ज	147.00	101.00	124.00	4.00 —
बिरला जूट	47.00	32.25	40.25	0.75 —
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	34.00	3.00 —
बॉम्बे डाइंग	159.50	94.00	141.00	2.00 +
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	87.00	—
ब्रुक बांड	98.00	75.00	84.00	3.00 —
सेंचुरी स्पिनिंग	875.00	617.50	830.00	45.00 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	64.50	2.00 —
कोलगेट	222.50	160.00	200.00	15.00 —
सायनामिड	52.00	33.00	42.00	1.00 —
डीसीएम	47.50	28.00	42.50	1.50 —
डनलप	86.50	69.50	72.00	4.00 —
ईआई होटल्स	54.00	38.00	49.00	1.00 —
एस्कार्ट्स	57.00	37.00	47.00	—
फिनोलेक्स केबिल्स	418.75	272.50	390.00	—
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	93.50	117.00	2.00 —
गरवारे नाइलोन	43.00	20.00	38.00	1.00 —
जी.ई. शिपिंग	33.75	20.80	26.75	2.25 —
गुजरात स्टेट फर्टि.	140.00	75.00	120.00	2.00 —
हासिम इंडिया	109.00	81.50	105.00	9.00 +
हिंदुस्तान सिबा	520.00	332.50	450.00	10.00 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	85.00	—
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	87.50	76.25	5.75 —
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	65.75	0.75 +
हिंदुस्तान मोटर्स	27.00	15.80	21.80	2.00 —
आई.ई.एल.	43.75	31.00	34.00	3.50 —
इंडियन आर्गेनिक	27.00	15.00	19.00	1.00 —
इंडियन रेयॉन	75.00	46.00	68.00	2.00 —
इंडाल	223.75	133.75	160.00	10.00 —
इगरसॉल-रैंड	335.00	205.00	245.00	2.00 —
आई.टी.सी.	46.00	30.00	39.50	1.75 —
जे.के. सिंथेटिक्स	74.00	45.50	62.25	2.25 —
काइनेटिक इंजी.	285.00	161.25	222.50	2.50 —
किर्लोस्कर क्युमिस	59.00	48.00	54.50	0.50 —
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	252.50	2.50 +
लारसन-टुब्रो	101.50	75.50	93.00	1.00 +
लिप्टन	67.00	52.00	61.50	0.50 —
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	13.25	1.75 —
मदुरै कोट्स	77.00	59.00	69.00	0.50 +
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	48.50	56.50	2.00 +
मिल्क फूड	140.00	72.50	120.00	5.00 +
मोटर इंडस्ट्रीज	630.00	447.50	547.50	22.50 —
मुकुंद आयरन	97.00	72.50	83.00	3.50 —
नेशनल आर्गेनिक	525.00	390.00	450.00	25.00 —
निरलॉन	16.00	5.00	9.50	1.00 —
ओरके सिल्क मिल्स	51.00	17.00	29.00	9.00 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	161.25	172.50	7.50 —
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	37.00	24.50	29.50	3.50 —
फाईजर	79.50	50.00	62.00	2.00 —
प्रीमियर ऑटो	39.50	23.00	29.00	8.00 —
रैनबेक्सी	120.00	70.00	80.00	3.00 +
रेमंड	96.00	41.50	49.00	0.50 —
रॉकिट एंड कोलमैन	227.00	175.00	212.00	1.00 —
रिलायंस इंडस्ट्रीज	231.00	69.00	181.00	20.50 —
शॉ वैलेस	132.00	50.50	54.50	0.50 —
श्रीराम फाइबर्स	62.50	32.50	50.50	3.50 —
सीमेंस इंडिया	80.00	56.00	64.00	1.00 —
एसकेएफ बैयरिंग्स	1365.00	1058.00	1275.00	5.00 —
स्पिक	60.25	23.50	45.25	0.75 —
टाटा स्टील	907.50	568.75	782.50	68.75 —
टेल्को	701.00	340.00	522.50	47.50 —
वाम आर्गेनिक	103.00	75.00	93.00	2.00 —
विम्को	24.00	11.00	16.50	0.25 —

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	क्रय मूल्य (रुपए में)	विक्री मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	11.2710	11.1520
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1040	1.0930
बहरीन	दीनार	1	37.3230	37.2186
बांग्लादेश	टका	100	38.4920	38.3790
कनाडा	डालर	1	11.7151	11.5955
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0474	2.0264
मिस्र	पौंड	1	9.3260	9.2130
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3419	2.2837
हांगकांग	डालर	1	1.8087	1.7903
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0830	0.0712
ईरान	रियाल	100	19.7332	19.6617
इटली	लीरा	100	1.0536	1.0000
जापान	येन	100	10.8225	10.5485
केन्या	शिलिंग	1	0.7832	0.7532
कुवैत	दीनार	1	50.0028	49.0136
मलेशिया	डालर	1	5.3968	5.3398
मारीशस	रुपया	1	1.0000	0.9832
नेपाल	रुपया	1	0.6128	0.5936
हालैंड	गिल्डर	1	6.8964	6.8255
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7832	0.7502
सिंगापुर	डालर	1	6.8981	6.8205
स्पेन	पैसो	1	0.1173	0.1092
श्रीलंका	रुपया	1	0.4562	0.4332
स्वीडन	क्रोना	1	2.2533	2.2295
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.3542	9.2564
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1536	0.1492
थाईलैंड	बहत्त	100	56.0382	55.9120
ब्रिटेन	पौंड	1	24.1750	24.0414
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	14.1343	13.9958
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.8560	3.8030
सोवियत संघ	रूबल	1	16.1820	16.1320
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	7.8864	7.6923

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 8.7.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एमआरटीपी

बदलता नजरिया

लाइसेंस प्रणाली उदार हुई

बड़े व्यवसायों की दुनिया बदल रही है. पर उसी हद तक जहां तक सरकार इजाजत दे. और सरकारी इजाजतें रुक-रुक कर आती हैं, कभी गहराई तक असर करने वाली तो कभी सिर्फ दिखावे भर की.

पिछले महीने के आखिर में सरकार ने अपनी औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में एक और बदलाव किया. यह प्रतीकात्मक ज्यादा थी, असरदार कम. नई छूट के तहत 69 कंपनियां एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कानून (एमआरटीपी) के बंधनों से अंशतः मुक्त कर दी गई. इनमें हर एक कंपनी अपने क्षेत्र की अगुआ (जैसे जूतों में बाटा, माचिसों में विमको) है.

मुख्यतः एक ही उत्पादन में 'एकाधिकार' रखने वाली यानी किसी भी क्षेत्र में कुल 25 फीसदी से भी ज्यादा उत्पादन क्षमता रखने वाली ये कंपनियां अब तक बड़े औद्योगिक एकाधिकार वाली उन कंपनियों के समकक्ष मानी जाती थीं जिनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रु. से ज्यादा है. इसलिए अपेक्षाकृत बहुत छोटी इन 69 कंपनियों को उर्वरक या पेट्रोरसायन जैसे किसी 'मूल' उद्योग में अपना विस्तार करने या ऐसे ही नए क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाजत दे दी गई. अब ये कंपनियां गैर-एमआरटीपी कंपनियों की तरह मानी जाएंगी और वे अपने उत्पादन क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में भी पांव फैला सकेंगी.

अभी एक महीने पहले सरकार ने एमआरटीपी और विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन कानून (फेरा) के तहत आने वाली कंपनियों से इतर कंपनियों को लाइसेंसों में भारी छूट देकर दूसरी बाधाएं भी हटा ली थीं. अब ताजा कदम के साथ ही बड़े उद्योगों की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं. उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "पहले जब लाइसेंस नियमानुसार जरूरी था तब शायद एमआरटीपी के तहत आने वाली दो तरह की कंपनियों में अंतर करना कोई खास मायने नहीं रखता था." लेकिन अब यह अर्थवान हो उठा है. वाम आर्गेनिक्स के कार्यकारी निदेशक एच.एस. भाटिया कहते हैं, "यह बात आसानी से गले नहीं उतरती थी कि हमारे जैसी छोटी-सी कंपनी उन क्षेत्रों में आजादी से प्रवेश क्यों नहीं कर सकती जहां हमारा दबदबा नहीं है."

अब तक ज्यादातर नियम तो गैर-एमआरटीपी और गैर-फेरा कंपनियों को ही ध्यान में रखकर उदार बनाए गए थे. एमआरटीपी कंपनियों को अब तक की आखिरी राहत नवंबर 1986 में दी गई थी. तब एमआरटीपी की परिधि में आने की सीमा 20 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 100 करोड़ रु. कर दी गई. पर असल में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. विभिन्न उद्योग लगातार तर्क दे रहे थे कि एमआरटीपी कंपनियों पर लगी अनगिनत पाबंदियां औद्योगिक वृद्धि की राह में आड़े आ रही हैं. एसोचैम के अध्यक्ष एल.एम. थापर कहते हैं, "अब बड़े उद्योगों के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है." उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एमआरटीपी और फेरा कंपनियों को बड़ी राहत देने का विचार मूर्त रूप ले रहा है.

एमआरटीपी और फेरा कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त करने के फैसले समेत नए कदमों का दूरगामी असर होगा. दरअसल 71 उपक्षेत्रों के लिए लाइसेंस की छूट तो पहले से ही थी, बशर्ते ये निवेश पिछड़े इलाकों में हों. गैर-एमआरटीपी कंपनियों को लाइसेंस की छूट देने के मामले में अब निवेश की सीमा 50 करोड़ रु. तक बढ़ा दी गई है. इसलिए अब शायद एमआरटीपी और फेरा कंपनियों के मामले में भी निवेश की यही सीमा तय कर दी जाए.

साथ ही यह भी लगता है कि दबदबे वाले उपक्रमों को परिभाषित करने का आधार भी बदल जाए. फिलहाल एक करोड़ रु. से ज्यादा की संपत्ति और किसी क्षेत्र में कुल उत्पादन क्षमता का 25 फीसदी रखने वाली कंपनियों को ही इसका फायदा मिला है. उद्योग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि यह सीमा क्रमशः 5 करोड़ रु. और 33 फीसदी तक बढ़ा दी जाए. इसके साथ ही कंपनियों के परस्पर संबंधों की धारणा में भी बदलाव हो सकता है. विभिन्न कंपनियों के निदेशक मंडलों और शेयर होल्डिंग के ढांचे में अगर थोड़ी बहुत भी समानता हो तो उन्हें उस एक औद्योगिक घराने का ही हिस्सा माना जाता है. पर संभवतः अब इस मानदंड में भारी बदलाव होगा.

कार्टून: अजीत नैनन

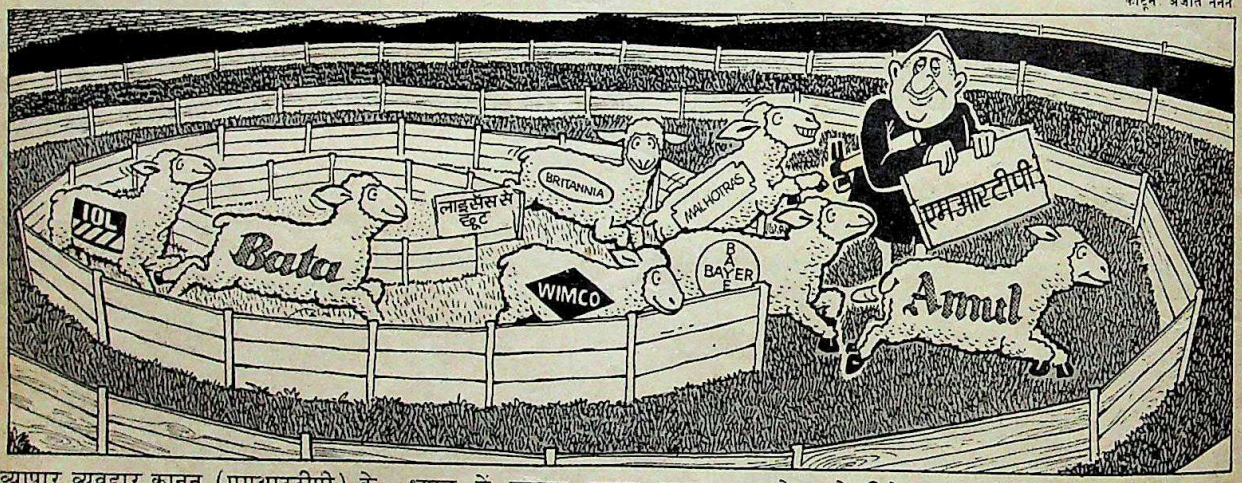

लेकिन एक बात तय है कि इन बदलावों का—अगर वे होते हैं तो— हर जगह एक-सा स्वागत नहीं होगा. जैसा कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के एस.के. गोयल कहते हैं, "नीतियों में बदलावों की झड़ी क्यों लग गई? इसीलिए कि सरकार के पास कोई ठोस खाका नहीं है. वह सिर्फ समय-समय पर विभिन्न दबाव गुटों के सामने झुक जाती है." राजनैतिक संवेदनशीलता से भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. इसीलिए इन प्रस्तावों के मूर्त रूप लेने की रफ्तार बहुत धीमी है. दरअसल 1986 में की गई पहल विचार के लिए हाल ही में मंत्रियों के एक दल के हवाले की गई है. चाहे जो हो, इतना तय है कि उदारवाद का दूसरा दौर तेजी से चलने लगा है.

—आनंद पी. रमन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Meet the Superstars of tomorrow...

Winners of
McDowell's Diplomat 'STARTRAX'

Music Talent Contest
Organised by

MUSIC INDIA

Three cheers for Jaydeep Swadia and Shankar Bhattacharya – the two magnificent additions to India's galaxy of musical stars!

The McDowell's Diplomat Startrax Music Talent Contest was started in August 1987. And received an overwhelming response in its first year. These entries were judged by eminent personalities from the Music Industry.

The best of each region were invited to perform at the semi-finals at Bombay, Delhi, Madras and Calcutta.

The winners of each regional contest then performed in Bombay on June 17, 1988 where the winners and runners up were chosen.

Runners up in the Hindustani Vocal category are Seema Anil Sehgal and Malini Awasthi. Deba Prasad Chakraborty is the runner up in the Instrumental category.

Prizes

Each of the winners received a trophy and a generous cheque of Rs. 25,000.
Each runner up got a trophy and a cheque of Rs. 10,000.

McDowell's
DIPLOMAT
STAR TRAX

Music Talent Contest
Organised by

MUSIC INDIA

OBM 2726

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेश्याओं के बच्चे

बदनामी बन गई बाधा

अछूतों जैसे व्यवहार से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय

नई दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद मार्ग के पास एक स्कूल में सुबह की प्रार्थना के समय पांच बच्चों को एक अलग पंक्ति में खड़ा किया जाता है. उन्हें दूसरे छात्रों के साथ घुलने-मिलने की इजाजत नहीं. इन उपेक्षित, प्रताड़ित बच्चों के लिए हर दिन पीड़ा और निराशा लिये ही आता है.

वजह यह है कि जी.बी. रोड के नाम से कुख्यात श्रद्धानंद मार्ग पर दिल्ली का वेश्या बाजार है और इन बच्चों ने उन्हीं वेश्याओं की कोख से जन्म लिया है. इन बच्चों (और इनकी अभागी माताओं) के लिए स्कूल में अछूतों जैसा बरताव उन चुनौतियों के मुकाबले मात्र एक छोटी-सी अड़चन है जिनका आगे उन्हें शिक्षित होने और जिंदगी संवारने के प्रयासों में सामना करना है.

पांच साल पहले पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वेश्यावृत्ति को मजबूर कलकत्ता की 30 वर्षीया शांति देवी ने हाल ही में अपने सात वर्षीय बेटे बबुआ का स्कूल छुड़वा दिया. बदनाम बस्ती सोनागाछी की शांति ने बबुआ को शिक्षा पूरी होने तक बेहतर माहौल में रखने की खातिर बड़ानगर प्रमोद भवन हॉस्टल में दाखिल करवाया था. अब बबुआ उन्हीं गलियों में खेलता है जहां उसकी मां ग्राहक पटाती है.

वेश्याओं के अभागे बच्चों को पालने और उनकी पढ़ाई-लिखाई में आने वाली समस्या राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में प्रकाश में आई जब देश भर में एक लाख की सदस्यता का दावा करने वाले दिल्ली के एक संगठन 'भारतीय पतिता उद्धार संघ' ने सुप्रीम कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की. सभा के अध्यक्ष खैरातीलाल भोला द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए वेश्याओं के बच्चों से पिता का नाम न पूछा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर करके केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. अब केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे दाखिला लेने वाले छात्रों को अपने पिता का नाम लिखने पर जोर न दें और मां का नाम ही पर्याप्त माना जाए. लेकिन यह तो उनके लिए अंधेरी और निर्मम दुनिया में उम्मीद की एक हल्की किरण भर है.

बंबई की बदनाम बस्ती कमाठीपुरा के महानगरपालिका स्कूल में 5,000 छात्रों में से वेश्याओं के भी 75 बच्चे हैं. शहर में निर्मला निकेतन के कॉलेज ऑफ सोशल वर्क से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति पई कहती हैं, "इन बच्चों के लिए कुछ करने की जरूरत है. यदि आप उनसे पूछें कि वे कहां रहते हैं तो वे नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है." कमाठीपुरा में करीब 7,000 वेश्याएं हैं. उनके बच्चों की संख्या भी लगभग 10,000 है. इनमें बमुश्किल 200 ही स्कूल जाते हैं. महानगरपालिका के स्कूल में 'प्रेरणा' नाम की एक संस्था छह साल से छोटे बच्चों के लिए एक शिशुगृह चलाती है. 23 बच्चों वाला यह शिशुगृह शाम के वक्त खुलता है जब उनकी माताएं ग्राहकों को आकर्षित करने में व्यस्त होती हैं. लेकिन इन माताओं को बच्चों को अलग करने के लिए मनाना भी आसान नहीं.

और जो बच्चे पढ़ने लगते हैं, वे भी अक्सर स्कूल के दबावों को बरदाश्त नहीं कर पाते. उन्हें घर पर पढ़ने-लिखने का मौका नहीं मिल पाता. इसलिए जब बच्चा बार-बार फेल होने लगता है तो वह स्कूल छोड़ने का मन बना लेता है. पई कहती हैं, "अंत में वे अपनी माताओं के ग्राहकों के लिए संदेशवाहक का काम करने लग जाते हैं." इसके साथ ही होती है अपराधी जीवन की शुरुआत, जैसे शराब का अवैध धंधा, नशीली दवाएं बेचना और वेश्याओं की दलाली करना. बच्चियां तो अमूमन 15 वर्ष की होते ही वेश्यावृत्ति में पड़ जाती हैं. सेंट ज़ेवियर कॉलेज के लेक्चरर और देह व्यापार दमन कानून की एक शोध परियोजना में काम कर चुके जीन डी'कुन्हा कहते हैं, "बच्चे के लिए पहचान की समस्या स्कूल से ही शुरू हो जाती है जब उससे पिता का नाम पूछा जाता है और वह बता नहीं पाता."

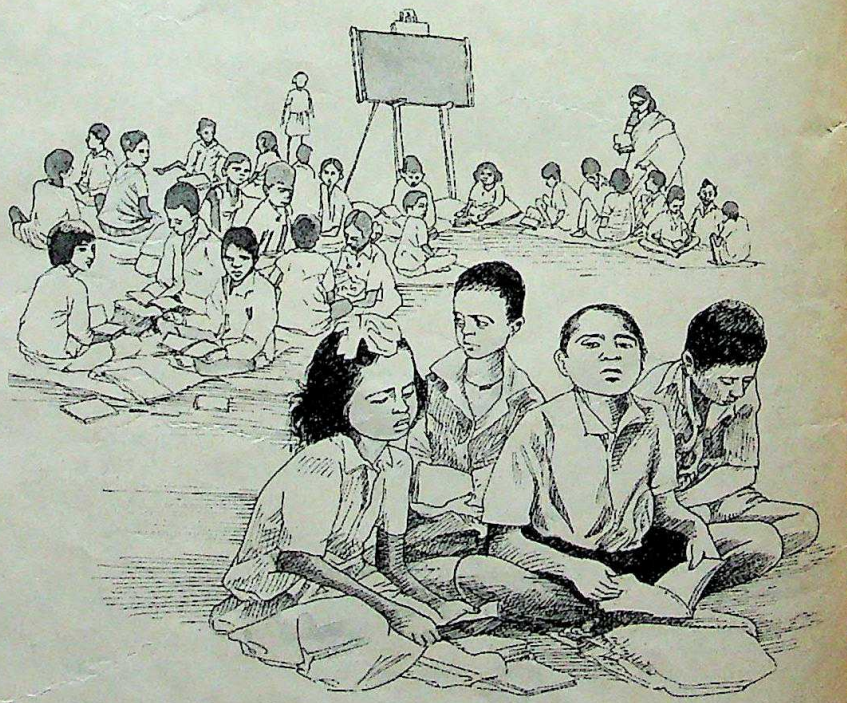

स्कूल में इन बच्चों के साथ अछूतों जैसा बरताव किया जाता है और वे निरंतर प्रताड़ित होते हैं. जो बच्चे पढ़ने लगते हैं, वे भी अक्सर दबावों को बरदाश्त न कर स्कूल छोड़ देते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी रेखाचित्र: मंजुला पद्मनाभन

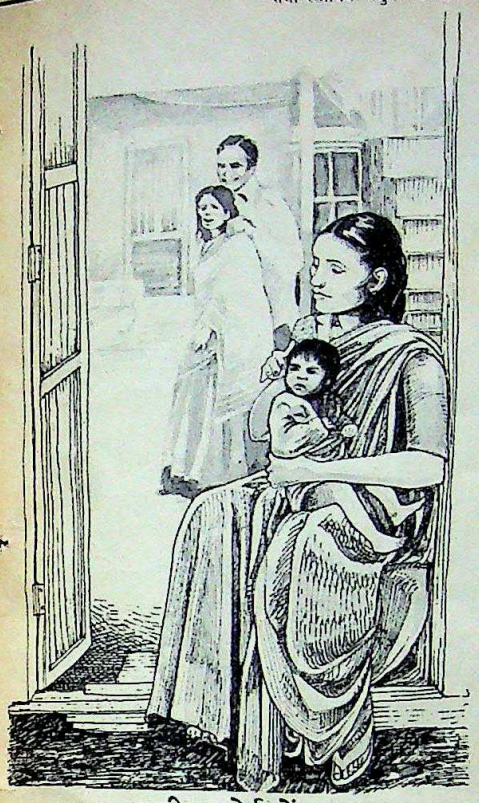

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होने के बाद केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे इन बच्चों को अपने पिता का नाम लिखने पर जोर न दें, मां का नाम काफी है

इसके बावजूद अधिकांश वेश्याएं अभी भी बच्चे जनना चाहती हैं. पई कहती हैं, "दरअसल बच्चे को ही वे एकमात्र अपना कह सकती हैं और बुढ़ापे में उसी के सहारे की उम्मीदें लगाए रहती हैं." उनकी कमाई भी बहुत कम होती है. अधेड़ उम्र (28 साल से अधिक) की वेश्या की आमदनी अमूमन 1,200 रुपए माहवार बैठती है. इसका आधा तो वेश्यालय के मालिक के पास चला जाता है.

कुन्हा कहते हैं कि इस गलीज माहौल में पल-बढ़ रहे बच्चे दलाली और नशीले पदार्थों की बिक्री जैसे धंधे ही अपनाने लगते हैं. "दूसरा कोई रास्ता नहीं. लड़कियों के लिए 'सम्मानजनक' पति ढूंढ़ना तो मुश्किल है ही."

न खत्म होने वाली मुसीबतें भी इन बच्चों को अनैतिकता के गर्त में धकेलती जाती हैं. दिल्ली की जी.बी. रोड की लक्ष्मी के दो बच्चे हैं—तीन साल का बेटा और छह माह की बेटी. उसका बेटा राजू अभी से उसे 'रंडी' कहता है. उदास लक्ष्मी बताती है कि राजू के शब्द भंडार में मां-बहन की गालियां भी शामिल हो गई हैं.

मद्रास की करुप्पई का 18 वर्षीय बेटा रमण पद्मनाभन पुराने शहर के जॉर्ज-टाउन की गलियों में घूमने वाला एक लफंगा है. करुप्पई ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की. "स्कूल में दाखिला मिलना मुश्किल था क्योंकि उसके लिए बच्चे के पिता का नाम लिखवाना जरूरी है और जब मैंने एक स्कूल में पिता का फर्जी नाम लिखवाकर उसे दाखिला दिला भी दिया तो उसका खर्च उठाना मेरे बूते से बाहर था." आखिर एक साल बाद ही उसे बेटे को स्कूल से निकाल लेना पड़ा.

बदनाम बस्ती के बच्चों के पास अपना पेट भरने के लिए अक्सर अपराध ही एक रास्ता बचता है. घिनौने और पाशविक जीवन का प्रशिक्षण बच्चे को पालने में ही मिलता है. इन कारणों से शैक्षणिक संस्थाएं इन बच्चों को शिक्षा देने की अपनी जिम्मेदारी से कंधा झटक देती हैं. शिक्षकों की यह आम शिकायत है कि ये बच्चे नहाए बिना ही चले आते हैं. उनमें अपराध प्रवृत्ति होती है. दूसरे बच्चे भी इनसे दूर रहते हैं.

बहुत दृढ़प्रतिज्ञ वेश्याएं ही अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा पाती हैं. मध्य कलकत्ता में रहने वाली लीला उन्हीं में से है. वह कहती है, "आप क्या सोचते हैं, मैं यहां खुश हूं? अब तक मैं हजार दफा मर चुकी होती. पर मैं खुदकशी भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक बेटा है और मैं चाहती हूं कि वह पढ़ाई में नाम रोशन करे." लीला ने अपने बेटे के लिए खासे खर्चे पर ट्यूशन भी लगा रखा है.

लेकिन बदनामी का कलंक इन अभागे बच्चों को कभी उबरने नहीं देता. एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में वेश्याओं की संख्या लाखों में है. पर उनके बच्चों की संख्या का कोई अनुमान भी नहीं. मसलन अकेले मद्रास में अनेक वेश्याएं अपने बच्चों को अनाथालयों के दरवाजों पर छोड़ जाती हैं. लेकिन अभी भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका भविष्य अंधकारमय है. भोला चाहते हैं कि इन बच्चों के लालन-पालन और पढ़ाई की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें उठाएं पर इसकी संभावना नहीं दिखती. जब तक कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे नहीं आतीं, उन्हें यह कलंक झेलते रहना होगा.

—कलकत्ता में कमलजीत रतन, दिल्ली में डेविड देवदास, मद्रास में एल.एच. वेंकटरमनी और बंबई में सलिल शिमली

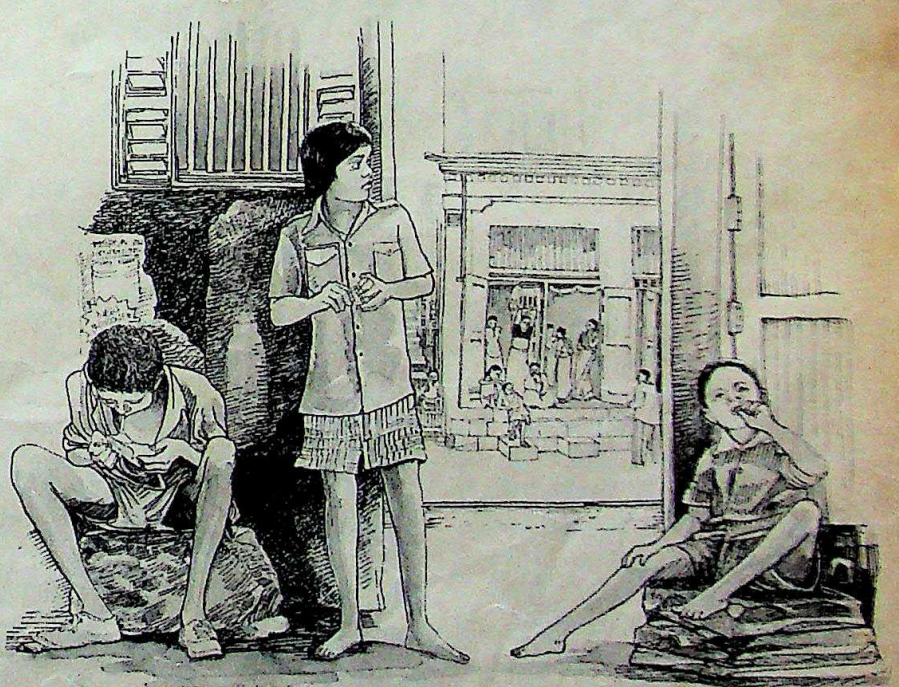

गलीज माहौल में पल-बढ़ रहे बच्चे वैसे ही धंधे सीख लेते हैं. लड़कियां वेश्यावृत्ति करने लगती हैं जबकि लड़के नशीले पदार्थों की बिक्री या वेश्याओं की दलाली करने लगते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

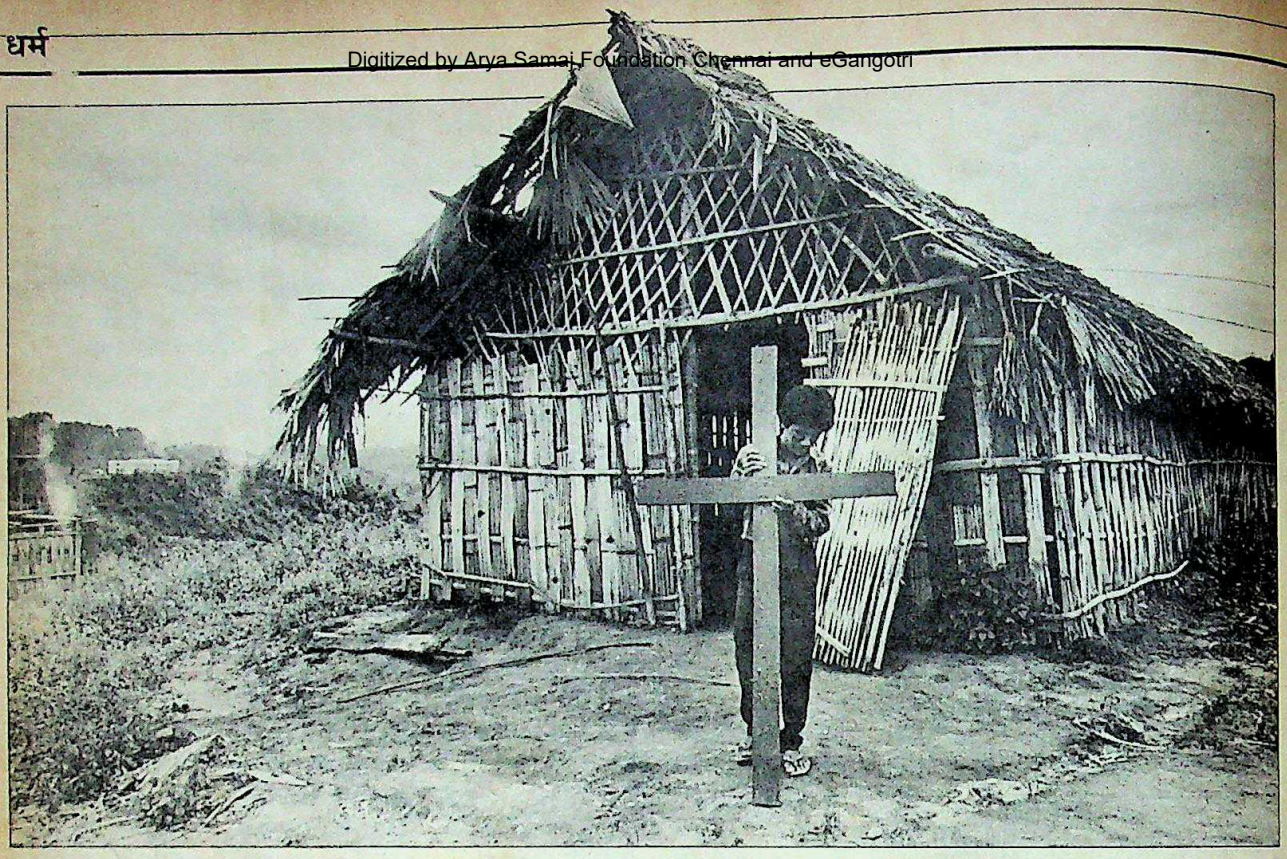

अरुणाचल प्रदेश

गांव का चर्च और नया ईसाई

समाज को सलीब का सहारा

धर्म परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार से कई तरह के तनाव भी बढ़े

पहाड़ियों के पीछे सूरज ढलते ही असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में हरमट्टी के सेंट जेवियर स्कूल के छात्र खेल के मैदान की ओर निकल पड़ते हैं. ईसाई पादरियों द्वारा चलाए जा रहे दूसरे स्कूलों की तरह यहां भी इस वक्त प्रार्थना करने का नियम है. लेकिन असम के ऐसे और स्कूलों के मुकाबले यहां एक बात निराली है—छात्रावास में रहने वाले 270 छात्रों में से 220 अरुणाचल प्रदेश के वनवासी हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कर ईसाई बना दिया गया है.

धर्म परिवर्तन का यह अकेला उदाहरण नहीं है. अरुणाचल की सीमा से लगते असम के जोरहाट, तेजपुर, लखीमपुर, नहरकटिया, डिब्रूगढ़, मार्घेरिता, डुमडुमा, गोलाघाट, तिनसुकिया, सोनारी, राजाबारी, सरूबथार, और बोकाघाट जिलों में ईसाई मिशनरियों की शैक्षिक संस्थाओं की बाढ़-सी आ गई है. (देखें नक्शा). दस साल पहले अरुणाचल प्रदेश की 8.5 लाख आबादी में सिर्फ 5,000 हजार ईसाई थे, आज निचले अरुणाचल में 60,000 से ज्यादा लोग ईसाई बन चुके हैं.

धर्म परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार से कई सामाजिक और धार्मिक तनाव तो पैदा हो ही रहे हैं, राज्य सरकार भी दुविधा में पड़ गई है. इस दुविधा का कारण 1978 में पारित अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है. इसका मसकद अरुणाचल प्रदेश के वनवासियों को ईसाई या दूसरे किसी धर्म में दीक्षित किए जाने से बचाना था.

लेकिन धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनते लोगों की बढ़ती संख्या ने विधेयक की धज्जियां उड़ाकर रख दी है. वह भी तब जबकि इस विधेयक के तहत राज्य में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है.

मिशनरियों ने असम से लगती राज्य की सीमा में चर्च, स्कूल और अस्पताल खोलकर इस अड़चन से पार पा लिया. असम के उत्तरी लखीमपुर जिले से लगते, 70,000 की आबादी वाले निचले सुबानसिरी जिले में ही 30,000 लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं. यहां के जिला इंका समिति अध्यक्ष तदार तानियांग का अनुमान है कि अगले एक दशक के भीतर राज्य की 70 फीसदी आबादी ईसाई बन जाएगी. वे कहते हैं, "हम इस विधेयक को लागू नहीं होने देंगे. यदि सरकार ने इसे हम पर जबरदस्ती थोपा तो हिंसा भड़क उठेगी. देश के दूसरे नागरिकों की तरह हमें भी अपना धर्म चुनने की आजादी होनी चाहिए."

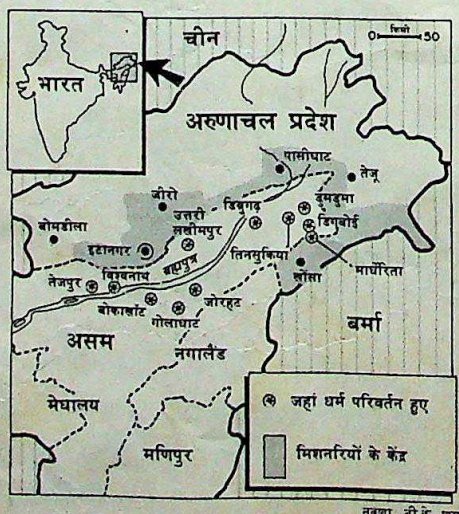

नक्शा: बी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के और भी कई कारण हैं. इनमें प्रमुख कारण आर्थिक है. अरुणाचल के 130 कबीले जीववाद में आस्था रखते हैं. उनके धर्म (जिसे स्थानीय भाषा में 'दोनिई पोलो' के नाम से जाना जाता है) में सूर्य और चंद्रमा की पूजा की जाती है. इस धर्म में खर्चीले कर्मकांडों की भरमार है. ज़रा-ज़रा-सी बात पर पशुबलि देना तो आम बात है.

एक औसत कबीलाई परिवार बूते के बाहर होते हुए भी हर साल ऐसी पशुबलियों पर तकरीबन 15,000 रु. खर्च करता है. इसके उलट ईसाई धर्म वनवासियों को महंगे कर्मकांडों से मुक्ति दिला देता है. 25 वर्षीय सरकारी ठेकेदार योरदा जॉन कहते हैं, "पशु बलि दे-देकर हम दिवालिया हो चुके थे. अब हम राहत महसूस करते हैं." पिछले पखवाड़े एक अधेड़ वनवासी महिला, नंगराम याप चार दिन पैदल चलकर ईसाई धर्म की दीक्षा लेने हरमट्टी के मिशन जा पहुंची. वह प्रेतात्माओं और उन्हें दूर करने के कर्मकांडों से छुटकारा पाना चाहती थी. प्रेतात्माओं की अनिष्टकारी छाया से हर वनवासी परिवार आतंकित रहता है. ईसाई मिशनरी उन्हें भरोसा दिला देते हैं कि ईसाई धर्म अपना लेने से इनसे हमेशा के लिए पिंड छूट जाएगा.

धर्म परिवर्तन की एक और वजह है. अरुणाचल में कबीलाई धर्म बहुत सुगठित नहीं है सो ईसाइयत जैसे सुगठित धर्म की ओर उन्हें खींचना बहुत मुश्किल नहीं है. और जब वनवासी धार्मिक पाखंडों से छुटकारा पाना चाहते हों तब तो यह काम और आसान हो जाता है.

लेकिन धर्म परिवर्तन के कारण सामाजिक तनाव पनपने लगा है. अरुणाचल में अब हिंदुओं और ईसाई मिशनरियों में शीत युद्ध शुरू हो गया है. हिंदू धर्म प्रचारकों को सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन मिला हुआ है. रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद केंद्र ने सरकारी सहायता से अरुणाचल में स्कूल और अस्पताल खोले हैं. इन स्कूलों का स्तर सरकारी स्कूलों से बेहतर है. ईसाई मिशनरियों का आरोप है कि इसी से सरकार का पक्षपाती रवैया साफ हो जाता है. मुख्यमंत्री गेओंग अपांग कैफियत देते हैं कि हिंदू संस्थाएं वनवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं करतीं.

लेकिन इस शीत युद्ध में जीत अंततः ईसाई मिशनरियों की ही होगी, क्योंकि वे अपने काम में शिद्दत से लगे हुए हैं. अपांग बताते हैं कि साधनों के मामले में तो उनका मुकाबला राज्य सरकार भी नहीं कर सकती. चिंता की बात तो यह है कि इन मिशनरियों के माध्यम से विदेशी तत्वों को नगालैंड और मिजोरम की तरह यहां भी अलगाववादी प्रवृत्तियों को भड़काने का मौका मिल रहा है. सबसे ज्वलंत उदाहरण अंग्रेज ईसाई धर्म प्रचारक रेवेरेंड स्कॉट का है. उन्हें नगा विद्रोह का जनक माना जाता है. भूमिगत नगा नेता फिजो को लंदन में शरण देने के पीछे भी यही शख्स था.

लेकिन उत्तर-पूर्व में फैले मिशनरियों में ज्यादातर केरल के हैं. अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित ये मिशनरी अरुणाचल के उन इलाकों में भी जा पहुंचे हैं जहां दशकों से कोई सरकारी अधिकारी नहीं गया. वनवासियों को वे सबसे जरूरी चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराते हैं. उनकी सेवाभावना से कई वनवासी प्रभावित होते हैं.

फादर फ्रांसिस थोट्टाथिम्यालिल ने गिरजाघर की प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करने के लिए 14 दिन तक राज्य के बीहड़ इलाकों की यात्रा की थी. गिरजाघर बनने पर पाबंदी की वजह से ईसाईबहुल क्षेत्रों में ज्यादातर गिरजाघर घासफूस के ही हैं. एक समर्पित ईसाई धर्म प्रचारक हेनरी गायकवाड़ ने भगवा चोला पहन अपना नाम प्रेम भाई

सेंट जेवियर स्कूल (नीचे); (सबसे नीचे) और भगवा वस्त्र में ईसाई धर्म प्रचारक प्रेम भाई

अरुणाचल प्रदेश में ईसाइयों की आबादी दस वर्षों में 5,000 से बढ़कर 60,000 हो गई. धर्म परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार से कई तरह के सामाजिक और धार्मिक तनाव पैदा हो गए हैं

नबी कोटी; प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रख लिया है. भारतीय गिरजाघरों को वे एक तरह से आश्रम ही समझते हैं.

इटानगर के बीचोबीच स्थित एक बस्ती के 52 में से 44 परिवार ईसाई धर्म अपना चुके हैं. ईसाई बन चुके एक नौजवान का कहना है, "जल्दी ही बाकी आठ परिवार भी ईसाई धर्म अपना लेंगे." इस बस्ती में तीन कच्चे गिरजाघर बन गए हैं. अरुणाचल की तराई में बसे असम के सोनितपुर जिले के तारासु गांव के 300 घरों में से 70 अब ईसाइयों के हैं.

हरमट्टी के नजदीक अरुणाचल की तराई में बसे गुमतो गांव में 25 के 25 निशि वनवासी परिवार ईसाई बन चुके हैं. इन परिवारों के नौजवान पश्चिमी वेशभूषा पहने दिखते हैं लेकिन बुजुर्गों ने परंपरागत वेशभूषा नहीं छोड़ी है. उनके गले में पड़े क्रॉस से ही पता चलता है कि वे ईसाई हैं. हाल ही में ईसाई बने किशोर वय के पीटर थोरदा कहते हैं, "मिशनरियों का नजरिया रूढ़िवादी नहीं है. वे हमारे निजी जीवन में बिलकुल दखलंदाजी नहीं करते." नए-नए ईसाई बने ताकर गीमिर कहते हैं, "जहां तक संभव हो, वे हमारी मदद करते हैं. इस नई संस्कृति की कुछ बातें—मोमबत्ती जलाना, गिरजे जाना अटपटी तो लगती है, पर धीरे-धीरे हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे."

लेकिन राज्य सरकार की नापसंदगी के कारण यहां ईसाइयत में कुछ दिलचस्प परंपराएं चल निकली हैं. अरुणाचल देश का अकेला राज्य है जहां कैथोलिक चर्च में पूजा-अर्चना पादरी नहीं करते. राज्य में उनका प्रवेश वर्जित है सो नए ईसाई बने लोगों में से ही एक को 'केटेकिस्ट' (धर्मोपदेशक) बना दिया जाता है. लेकिन वह सिर्फ दैनिक प्रार्थनाओं का ही संचालन कर सकता है, धार्मिक सभाओं को संबोधित करने का अधिकार उसे नहीं. बिशप थॉमस मनमपारंबिल बताते हैं, "कैथोलिक ईसाइयों को धर्म सभाओं के संचालन और 'कन्फेशन' (अपने अपराध की स्वीकारोक्ति) सुनने के लिए पादरियों की जरूरत होती है. उनके बिना लोगों की आध्यात्मिक जरूरतें नहीं पूरी हो पातीं. लेकिन अरुणाचल सरकार इस समस्या को समझ नही रही. हमें राज्य के ईसाइयों के आध्यात्मिक विकास की भी चिंता है."

हालांकि इस दौड़ में ईसाई मिशनरी हिंदू संगठनों से कहीं आगे हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे यह धार्मिक लड़ाई जीत गए हैं. राज्य के वित्तमंत्री लोरिंग ताशें कहते हैं, "हमारी इजाजत भर मिल जाए तो ये मिशनरी राज्य का स्वरूप बदलकर रख देंगे." असम के अधिकारी भी अब सतर्क हो गए हैं. वे सीमावर्ती क्षेत्रों में मिशनरियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा रहे हैं.

लेकिन मिशनरियों को इस सरकारी विरोध की अब रत्तीभर भी परवाह नहीं. ईसाई धर्म के कुछ प्रकाशनों में तो खुलेआम कबूल किया गया है कि उनका काम अब पहले के मुकाबले आसान हो गया है. कुछ साल पहले तक मिशनरी राज्य में ईसाइयों के साथ होने वाले पक्षपात का राग अलापते थे लेकिन ऐसा करने से हिंदू संगठनों का ध्यान उन पर केंद्रित हो जाता है, सो ईसाई मिशनरियों ने यह रवैया अपनाना बंद कर दिया है.

राज्य में ईसाइयों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण राजनैतिक दलों का उनके प्रति नजरिया बदल रहा है. अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के अध्यक्ष टोमो रिबा का कहना है कि चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए मिशनरियों को राज्य में काम करने की अनुमति दे देनी चाहिए.

अरुणाचल सरकार को अंदेशा है कि ये मिशनरी उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुलग रहे अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी आंदोलन को और भड़का देंगे. पर मिशनरियों का कहना है कि यह डर बिलकुल बेबुनियाद है. फादर चेरियन कहते हैं, "राष्ट्र विरोधी भावनाएं भड़काने का आरोप बिलकुल गलत है, हम तो इन वनवासियों को शिक्षित कर रहे हैं. शिक्षित होकर वे अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं तो दोष हमारे मत्थे मढ़ दिया जाता है."

लेकिन राज्य सरकार के लोगों को भी लगने लगा है कि यह धर्म परिवर्तन अपरिहार्य है. उद्योगमंत्री तोदाक बासर कहते हैं, "यह तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि भविष्य के हितों को ध्यान में रखते वे धर्म परिवर्तन करें."

—रमेश मेनन, अ.प्र. में

नए ईसाई गीमिर चर्च की कार्यवाही चलाते; और (सबसे नीचे) फादर चेरियन गांव का दौरा करते

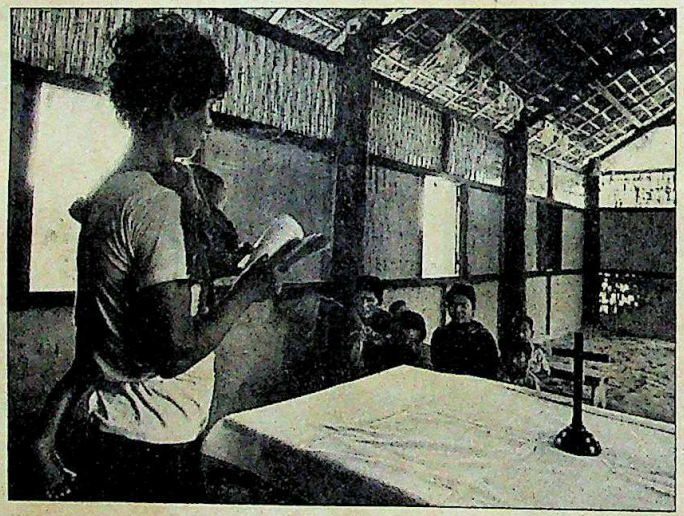

अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित ये ईसाई धर्म प्रचारक अरुणाचल के उन इलाकों में भी पहुंचे हैं जहां दशकों से कोई सरकारी अधिकारी नहीं गया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंतजार और हक्के-बक्के

मनोरंजन का नया मसाला

भाषणबाजी के बदले कॉमेडी के जरिये गंभीर संदेश

जब से दूरदर्शन ने सीरियल परंपरा की नींव डाली है तब से हिंदुस्तानी टीवी दर्शकों के घरों में आए दिन 'लल्लू', 'लाजोजी', 'मास्टरजी', 'रजनी', 'गुप्ताजी', 'घंसू', और 'खोपड़ी' जैसे चरित्रों का जमघट लगा ही रहता है. इस जमघट की एक खूबी यह है कि मौसमी फूलों की तरह ये चरित्र दर्शकों के बैठकखाने में आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और फिर अगली पौध के फूलों के लिए रास्ता छोड़ते हुए यादों के झुरमुट में खो जाते हैं.

इन दिनों घरों में जो नाम चर्चित हैं उनमें रामायण के पात्रों के बाद 'मौसा चाचा', 'भैयू', 'चिची', 'पिंकू', 'मंगल', 'शामू', 'बांके' और 'हवलदार' जैसे नाम हैं. जून के अंतिम सप्ताह में एक सर्वेक्षण संगठन ने देश भर के कुछ प्रमुख नगरों का मुआयना करने के बाद पाया कि रामायण और हिंदी फिल्म जैसे परंपरा से लोकप्रिय कार्यक्रमों के बाद प्रसिद्धि की सीढ़ियों पर 'इंतजार' और 'हक्के-बक्के' भी अपनी जगह बना चुके हैं.

इस सर्वेक्षण के अनुसार 'रामायण' को देखने वाले दर्शकों का राष्ट्रीय अनुपात 84 फीसदी है और फिर हिंदी फीचर फिल्म के बाद 'इंतजार' (57) और 'हक्के-बक्के' (56) का स्थान है. इन सीरियलों के मुकाबले 'चित्रहार' की लोकप्रियता केवल 53 फीसदी पाई गई.

इन दोनों सीरियलों की खूबी है कि दोनों ही बाकी सीरियल-बिरादरी से काफी हटकर हैं. 'इंतजार' अपने पुराने शहरी संस्करण 'नुक्कड़' का ग्रामीण अवतार है और सांप्रदायिकता, आतंकवाद तथा असमानता के सदमे से ग्रस्त दर्शकों के लिए हर हफ्ते उस आदर्श समाज के सपने बुनता है जो फिलहाल केवल कल्पना की दुनिया तक सीमित है. सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा और कुंदन शाह की तिकड़ी इस फन में खासी माहिर हो चुकी है.

'हक्के-बक्के' की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण तो यही है कि यह इन दिनों दिखाई जाने वाली एकमात्र कॉमेडी है. और यह भी कि टीवी के इतिहास में पहली बार परिवार नियोजन का संदेश सरकारी भाषणबाजी के बजाय कॉमेडी के माध्यम से आ रहा है. इस गंभीर विषय को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करने के बारे में निर्माता-निर्देशक रवि बासवानी कहते हैं, "हमारा नजरिया यह है कि फैमिलीप्लैनिंग जैसे गंभीर सवाल को सिर्फ मां-बाप तक सीमित न रखा जाए बल्कि बच्चों समेत पूरे परिवार के सामने रखा जाए ताकि वे आमने-सामने बैठकर इसकी गंभीरता को समझ सकें. इसलिए हमारे 'टूल' भी बच्चे हैं और 'टारगेट' भी बच्चे हैं."

(बाएं से) सुष्मिता, रवि और प्रिया: समस्याएं मुसीबत बनीं

सीरियल का प्लाट बहुत सीधा सादा है: दीदी (सुष्मिता मुखर्जी) अपने निखट्टू पति (जयंत कृपलानी) से तंग आकर अपने पांच ऊधमी बच्चों के साथ अपने नव विवाहित जीजा-देवर (रवि) और बहन (प्रिया तेंदुलकर) के घर डेरा जमा लेती है. बच्चों की खुराफातें मौसा-चाचा को जेल तक ले जाती हैं. बेचारे को बिना समझाए ही समझ आ जाता है कि घर में कितने बच्चे चाहिए.

बच्चों के इस अनूठे इस्तेमाल का कमाल यह हुआ है कि भैयू (सुमीत), मुन्नी (पूजा), पिंकू (सिद्धार्थ), चिची (सोनाली उर्फ 'किशमिश') और कटोरी (घर में मी 'कटोरी') की सूरत देखने और उनकी खुराफातों का लुत्फ उठाने के लिए दर्शक बच्चे अब बेसब्री से सोमवार की शाम का इंतजार करने लगे हैं.

बच्चों के चुनाव के बारे में मजेदार बात यह है कि इनमें से कोई भी पहले से प्रशिक्षित नहीं था. बासवानी ने दिल्ली के कुछ स्कूलों में जाकर खुद इन बच्चों को चुना और उन्हें अभिनय की घुट्टी पिलाई. पिछले पखवाड़े जब दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित नोएडा कॉलोनी में इस सीरियल के 11वें एपीसोड की शूटिंग चल रही थी उन दिनों ये बच्चे अपने स्कूल से सीधे नोएडा पहुंचते और शूटिंग के दौरान मिलने वाली छुट्टी में होमवर्क करते. बच्चों के आसपास बुनी गई इस कहानी में बच्चों का 'मौसा-चाचा' (रवि बासवानी) बार-बार एक से दूसरी मुसीबत में फंसता है. ये मुसीबतें—भले ही वह बच्चों के स्कूल एडमीशन की हों, पड़ोसियों से झगड़े की हों या फिर घर में पैसे की किल्लत से जुड़ी हों—हर हफ्ते याद दिला जाती हैं कि कम बच्चे हों तो समस्याएं गहराती नहीं हैं.

कुल मिलाकर ये दोनों सीरियल अपनी-अपनी तरह के मसालेदार व्यंजन हैं. लेकिन दूसरे सीरियलों के मुकाबले 'इंतजार' और 'हक्के-बक्के' की सफलता यह दिखाने के लिए काफी है कि दर्शक के स्वाद के मुताबिक मसाला बटोरना भी एक कला है.

—विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हंपी खंडहर

बीते वैभव की वर्णिका

विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडहरों के प्राचीन चित्र मिले

"बीजानगर जैसा शहर पूरी दुनिया में न तो कहीं देखा और न कहीं सुना."

दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में 15वीं शताब्दी में फारस के राजदूत अब्दुर रज्जाक ने यही लिखा था. उस वैभवशाली नगर के खंडहर अब कर्नाटक के बिलारी जिले के हंपी गांव में उपेक्षित पड़े हैं.

पुरातत्वविदों की बिरादरी में हंपी खंडहरों के नाम से चर्चित इस स्थान के इतिहास में इस महीने एक और अध्याय जुड़ जाएगा. कर्नाटक का पुरातत्व व संग्रहालय निदेशालय (केडीएएम) 200 पेज की एक पुस्तक जारी करने जा रहा है जिसमें विजयनगर के वैभवशाली अतीत और त्रासद वर्तमान का ब्यौरा होगा.

पहली बार बंगलूर में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें हंपी खंडहरों के 1856 और 1983 में खींचे गए छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे. एक सेट उन 60 छायाचित्रों का होगा जो 1856 में ब्रिटिश सैनिक अधिकारी व छायाकार एलेक्जेंडर जे. ग्रीनलॉ ने खींचे थे. इसी से मिलते-जुलते 1983 के छायाचित्र आस्ट्रेलियाई छायाकार जॉन गोलिंग्स के होंगे.

इन खंडहरों पर 1980 से शोध कर रहे ब्रिटिश कला इतिहासकार जॉर्ज मिशेल का कहना हैं, "ग्रीनलॉ के छायाचित्रों का महत्व यह है कि भारत के किसी भी प्राचीन स्थल के ये सबसे पुराने छायाचित्र हैं." इन छायाचित्रों को खोज निकालने में मिशेल ने अहम भूमिका निभाई है.

इंग्लैंड के कॉर्नवाल में बसे रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक अधिकारी एड्डि गिब्बंस ने 1980 में ग्रीनलॉ के वंशजों से छायाचित्रों के 70 निगेटिव खरीदे जो मोम की तह में सुरक्षित रखे गए थे. मगर वे समझ नहीं पाए कि ये निगेटिव किस स्थान के छायाचित्रों के हैं. लंदन के विक्टोरिया ऐंड अल्बर्ट संग्रहालय में भारतीय खंड की देखभाल करने वाले क्यूरेटर ने उन्हें मिशेल के पास भेज दिया. मिशेल ये पुराने निगेटिव देखकर उछल पड़े. उन्होंने अपने दोस्त गोलिंग्स को साथ लिया और हंपी पहुंच गए. उन्हीं कोणों से खंडहरों के फोटो फिर खिंचवाए. कई बार तो कैमरे की तिपाई ठीक उसी जगह रखी गई जहां रखकर ग्रीनलॉ ने तस्वीर खींची थी. केडीएएम ने 1985 में इन 120 छायाचित्रों को अपने कब्जे में ले लिया.

ग्रीनलॉ के छायाचित्र संयोजन व स्पष्टता में बेजोड़ हैं. इनके निगेटिव बहुत लंबे-चौड़े— 18 × 22 इंच— थे. इसी से जाहिर है कि इसके लिए उन्होंने कितना भारी-भरकम कैमरा और दूसरे साज-सामान ढोए होंगे. तब छायांकन की विधा का

1856

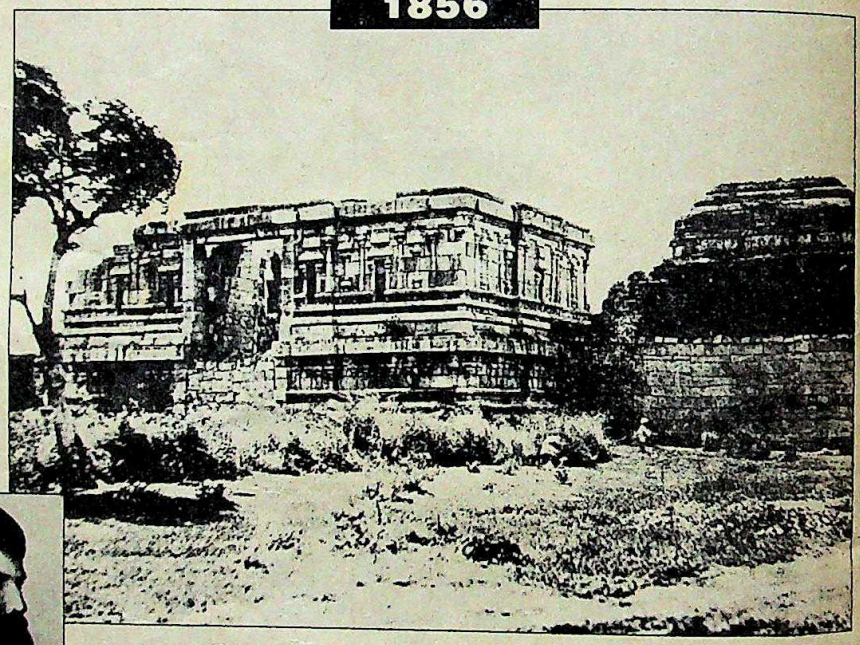

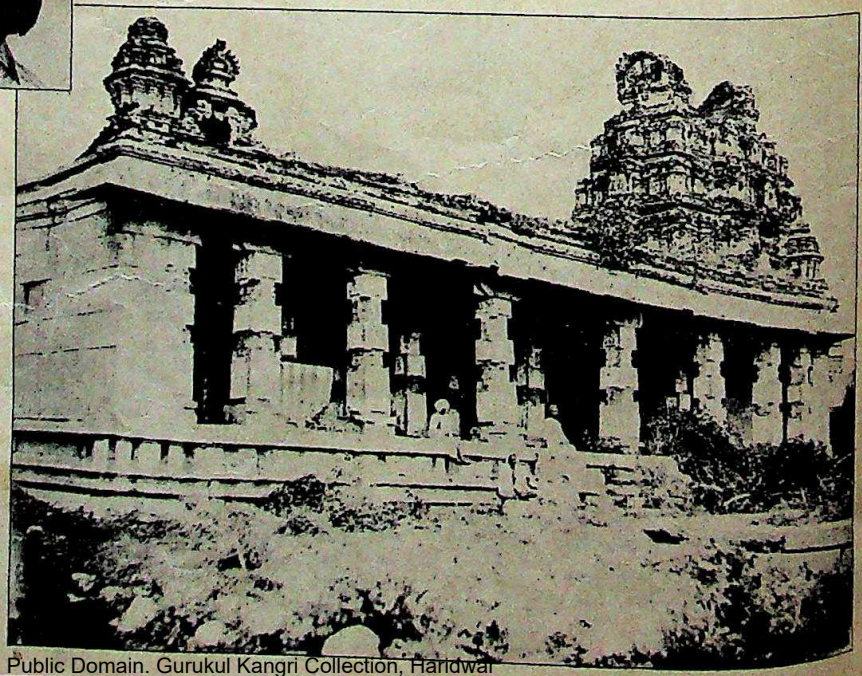

(ऊपर) अनंतशयन मंदिर का मुख्यद्वार; (नीचे) विट्ठल मंदिर का मंडप; और छायाकार ग्रीनलॉ: अमूल्य छायाचित्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आविष्कार हुए बस 20 ही साल गुजरे थे.

केडीएएम के निदेशक और प्रदर्शनी के कर्ताधर्ता डॉ. एम.एस. नागराजराव कहते हैं, "ग्रीनलॉ के छायाचित्र हंपी की सबसे पुरानी तस्वीरें हैं." इन तरतीबवार छायाचित्रों में बहुत-सी ऐसी सचाइयां दर्ज हैं जो 1856 के बाद लुप्त हो गईं. कई इमारतें समय की मार के चलते ढह गईं. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन तस्वीरों से अब कई इमारतों के संरक्षण व उनके पुनरुद्धार में मदद मिलेगी. मिसाल के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 19वीं शताब्दी की तस्वीरों के आधार पर कृष्ण और विट्ठल मंदिरों के कुछ हिस्सों के पुनरुद्धार का काम शुरू कर दिया है. मिशेल बताते हैं, "सिर्फ ग्रीनलॉ के छायाचित्रों से ही हमें पता चल सका कि विट्ठल मंदिर के सामने एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया एक स्तंभ था, जो अब नष्ट हो चुका है."

ग्रीनलॉ ने ज्यादातर छायाचित्र विट्ठल मंदिर के ही खींचे हैं. जाहिर है कि वे इस मंदिर की खूबसूरत नक्काशियों से काफी प्रभावित थे. उन्होंने विजयनगर में वास्तु-शिल्प की हर शैली को बहुत सावधानी से कैमरे में कैद किया है— चाहे वह हजारा राम मंदिर की नक्काशीदार मूर्तियां हों या राजा का निजी पूजाघर. इन दोनों निर्माणों को विजयनगर हिंदू मंदिरों के वास्तुशिल्प का सबसे सटीक उदाहरण माना जाता है.

नागराज 1983 से ही सरकार से मांग करते रहे हैं कि पांच किलोमीटर त्रिज्या (हंपी खंडहरों के महानवमी डिब्बा को केंद्र मानते हुए) के इलाके को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि वहां किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लग सके. हालांकि सरकार इससे सहमत है, पर रोक अभी लागू नहीं हुई है. नतीजा यह है कि वहां तमाम ऊटपटांग इमारतें बनती जा रही हैं जो इन खंडहरों की शान में बट्टा लगाती हैं. गोलिग्स के छायाचित्रों से साफ पता चलता है कि बिजली की तारों, नियॉन बल्बों, आधुनिक सड़कों और इमारतों ने इन खंडहरों के माहौल को किस कदर बिगाड़कर रख दिया है. गुलाबी-हरे ग्रेनाइट पत्थरों के लिए पहाड़ियों की खुदाई और खेती-बाड़ी ने स्थिति को और बदतर ही बनाया है.

विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अपनी भव्यता और खूबसूरती से जिस तरह मध्य युग में फारसी और रूसी यात्रियों का मन मोह लेती थी वैसे ही आज इसके खंडहर भी सैलानियों के आकर्षण के केंद्र हैं. ये खंडहर उस दौर के मूक गवाह हैं जिसमें भारत ने अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे दिन देखे थे.

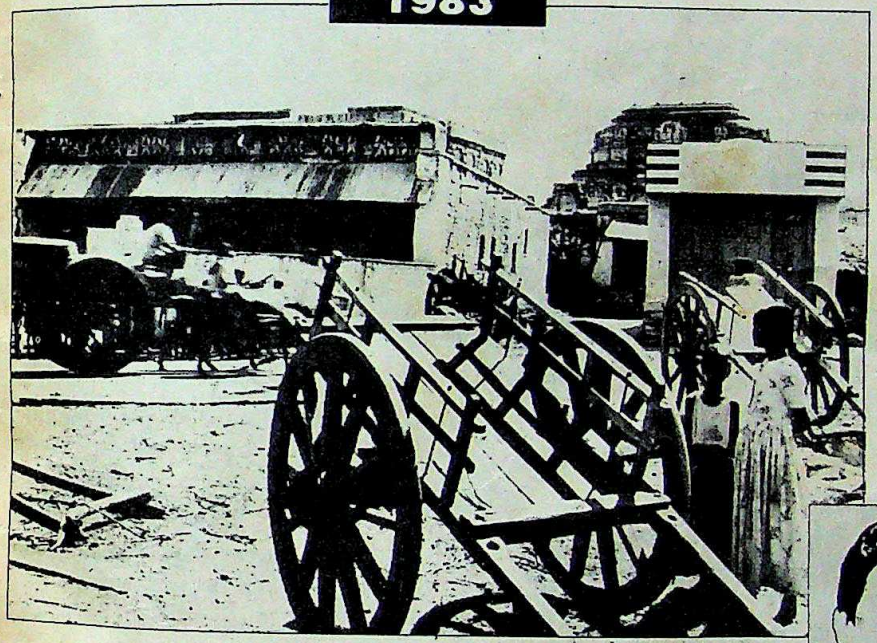

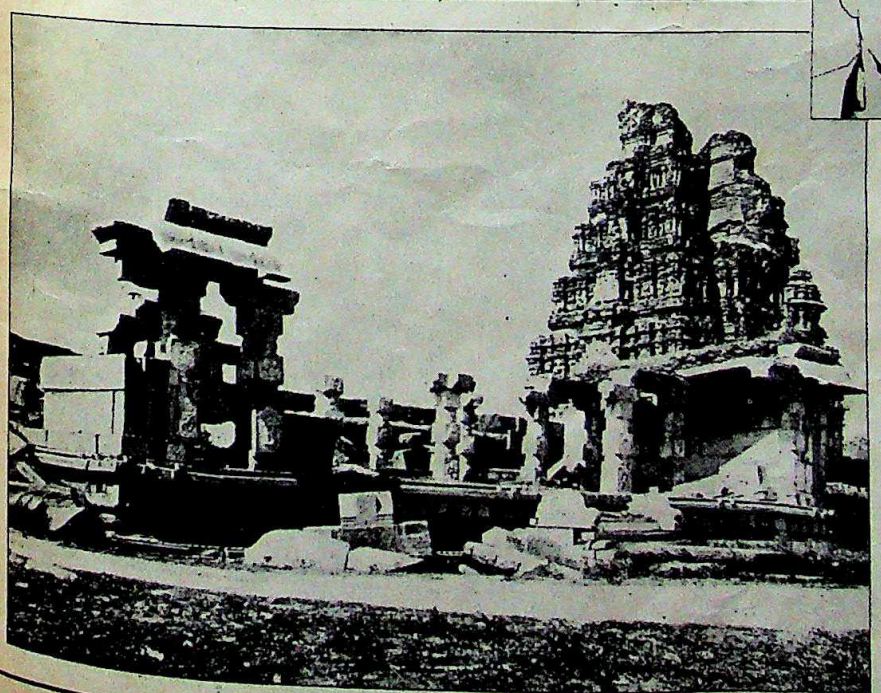

मध्य युग के महान हिंदू साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी. मुस्लिम विस्तारवाद को रोकने के लिए इस साम्राज्य को कायम किया गया था. 200 साल में ही यह साम्राज्य अपने वैभव, अपनी वास्तु-शिल्पी भव्यता और अपने सांस्कृतिक व साहित्यिक उत्थान के शिखर पर पहुंच गया था. 1520 में विजयनगर की यात्रा करने वाले पुर्तगाली सैलानी डोमिनिगो पेस की टिप्पणी गौरमतलब है, "यहां के बाजारों में दुनिया की हर वह चीज बिकती है जिसे खरीदने की आप इच्छा कर सकते हैं. यह दुनिया का सबसे सुविधासंपन्न शहर है."

पर समय बीतने के साथ ही यह साम्राज्य भ्रष्ट और निरंकुश हो गया. ओछी चाल-बाजियों, दरबारी साजिशों और बांटो व राज करो की नीति के कारण अंततः इस पर कहर

(ऊपर) अनंतशयन मंदिर का मुख्यद्वार; (नीचे) विट्ठल मंदिर के खंडहर; और छायाकार गोलिंग्सः दुर्दशा का बयान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टूट पड़ा. 1556 में चार पड़ोसी राज्यों के सुलतानों की मिलीजुली फौज ने इस पर हमला किया और तालीकोटा की लड़ाई में यह शहर तबाह कर दिया गया. इतिहासकार आर. स्वेल ने 1900 में अपनी रोचक पुस्तक 'ए फारगॉटन एंपायर' में लिखा है, "इससे पहले कभी किसी इतने संपन्न शहर के साथ इतना भयावह हादसा इतना अचानक नहीं हुआ था. संपन्न और उद्यमी आबादी से भरापूरा शहर एक ही दिन में दुर्दांत नरसंहार व लूट-खसोट के नजारों के बीच दारिद्रय की प्रतिमूर्ति बन गया."

नवंबर 1986 में यूनेस्को ने हंपी को 'एक अनूठी मानवीय कृति' की मान्यता देते हुए विश्व विरासत का दर्जा दिया. इसके संरक्षण के अब अंतरराष्ट्रीय मानदंड बना दिए गए हैं. इससे पहले 1976 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षामंत्री नूरुल हसन ने हंपी को खंडहरों की खुदाई की तीन राष्ट्रीय परियोजनाओं (दो दूसरी हैं— उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी और गुजरात में चंपानेर) में शामिल करने की घोषणा की थी. 1981 में कर्नाटक सरकार ने यहां हंपी पुनरुद्धार परियोजना शुरू की.

एएसआई 1902 से ही इन खंडहरों के सुधार और संरक्षण में लगा हुआ है. ग्रीनलॉ की तस्वीरें इस लिहाज से काफी अहमियत रखती हैं. उनकी मदद से लोग उस वैभव का अंदाज लगा सकेंगे जब राजा हरे चमकीले कपड़ों में मोतियों का कालर पहने महानवमी डिब्बा पर रखे हीरे-जवाहरात जड़े स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर महानवमी के उत्सव का आनंद लेता था. आतिशबाजी चलती थी, सजीले हाथियों के जुलूस निकलते थे, जादूगरों के तमाशे और पहलवानों के अखाड़े लगते थे और एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए प्याले में लबालब दूध भरा होता था जो गरीबों में बांटा जाता था. इन तस्वीरों से कुछ और अक्स भी कल्पना में उभरते हैं— सुंदर परिधानों में सजीधजी नर्तकियों के, जिन्हें राजा की मौजूदगी में भी पान चबाने का विशेषाधिकार मिला हुआ था; सोने के गहनों से लदी-फदी औरतों के, जिनके लिए चल पाना मुश्किल हो; लंबे-चौड़े बाजारों के जहां कीमती पत्थरों, मूंगे, रेशम और कमखाब की बिक्री और खरीदारी हो रही हो.

लेकिन ये छायाचित्र हंपी खंडहरों की त्रासदी भी उजागर करते हैं कि अतिक्रमण, नियॉन बल्बों और बिजली के खंभों ने प्राचीन भारत के एक सबसे खूबसूरत विरासत के वैभव को किस तरह तहस-नहस कर दिया है.

—अनीता प्रताप

पश्चिम बंगाल

अयोध्या की ओर

दार्जिलिंग का विकल्प ढूंढ़ लिया

पश्चिम बंगाल में हिमालय की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले दार्जिलिंग के शांत शंकुल वनों से लेकर सूखे और पिछड़े जिले पुरुलिया की अयोध्या पहाड़ी के साल वनों तक ढलवा जमीन है. राज्य में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र दार्जिलिंग समुद्री सतह से 2,134 मीटर की ऊंचाई पर है जबकि अयोध्या पहाड़ी मात्र 440 मीटर की ऊंचाई पर है. लेकिन दार्जिलिंग में गोरखालैंड आंदोलन की हिंसा के कारण पर्यटकों ने वहां जाना छोड़ दिया जिससे राज्य सरकार की आमदनी में हर साल करीब एक करोड़ रु. का नुकसान हो रहा है. लिहाजा राज्य सरकार कलकत्ता से कोई 300 किमी की दूरी पर पड़ने वाली अयोध्या पहाड़ी को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए मजबूर हो गई है.

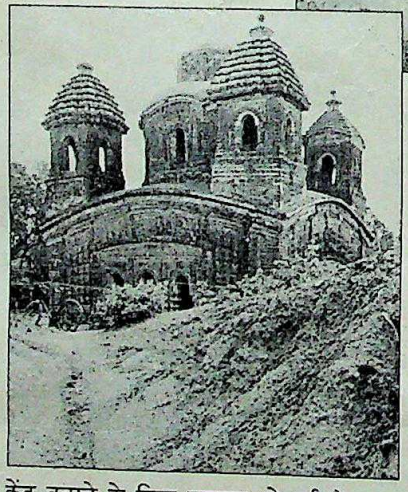

राज्य में फैली हुई पर्वत श्रृंखला दार्जिलिंग के बाद सिर्फ पुरुलिया में ही है और इसकी सबसे ऊंची चोटी अयोध्या है. साल वनों से घिरे इस पर्वत पर दो जलप्रपात और झरने हैं. सरकार यहां के 50 बिस्तर वाले होस्टल में आवास की सुविधाएं बढ़ाकर दुगनी कर रही है और अगल-बगल की छोटी पहाड़ियों पर पर्यटकों के लिए झोंपड़ियां बना रही है. सरकार की एक शिकारगाह बनाने की भी योजना है.

समूचे पुरुलिया और उससे सटे हुए बांकुड़ा जिले को भी आकर्षण का केंद्र बनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं. कांसावती बांध के पास मुकुटमणिपुर और झिलिमिली की मनमोहक सुंदरता एक जगह आराम से पड़े रहने वाले पर्यटकों को बांधे रखेगी जबकि सुसुनिया की पहाड़ियां साहसी पर्यटकों को अपनी तरफ खींचेंगी.

बांकुड़ा जिले में आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे पक्की मिट्टी के बने हुए मशहूर मंदिर. इन्हें मल्ल राजाओं ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी विष्णुपुर में बनवाया था. इनके अलावा पंचरत्न मंदिर भी, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है. पास के तीर्थस्थलों कामारपुकुर और जयरामबाटी को भी सुंदर बनाने की योजना है. कामारपुकुर श्री रामकृष्ण परमहंस और जयरामबाटी मां शारदा देवी की जन्मस्थली है.

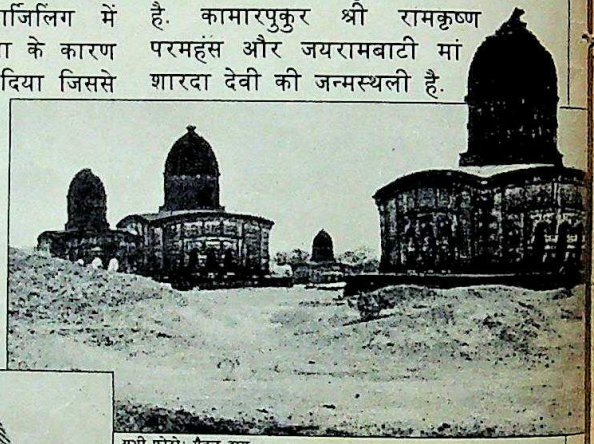

सभी फोटो: सैबल दास

विष्णुपुर का पंचरत्न मंदिर (बाएं); और बांकुड़ा के मंदिर: नए पर्यटनस्थल

पर्यटकों के आकर्षण के लिए मशहूर सुंदरवन का भी विकास किया जा रहा है. पर्यटकों के ठहरने के लिए हाल ही में बक्खाल और साजनेखाल में दो टूरिस्ट लॉज बनाए गए हैं. राज्य की विद्युत परिषद ने इस इलाके के लिए एक सौरबिजली परियोजना का प्रस्ताव किया है. राज्य के पर्यटनमंत्री सुभाष चक्रवर्ती कहते हैं, "हम इस वर्ष कुल मिलाकर लगभग छह करोड़ रु. खर्च करेंगे." राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान भी शुरू किया जाएगा. चक्रवर्ती अब खेद जताते हैं कि राज्य ने कई वर्षों तक दूसरे पर्यटन केंद्रों की उपेक्षा की. वे कहते हैं, "दार्जिलिंग में हम सालाना लगभग 35 लाख रु. खर्च कर रहे हैं जबकि वहां के अधिकतर विश्राम स्थल जला दिए गए हैं. इससे 5 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है."

यह एक महंगा सबक है. लेकिन सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि दार्जिलिंग के प्रेमी पर्यटक क्या अब सैर के लिए अयोध्या पहाड़ी पर जाएंगे?

—कमलजीत रतन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यदि आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए

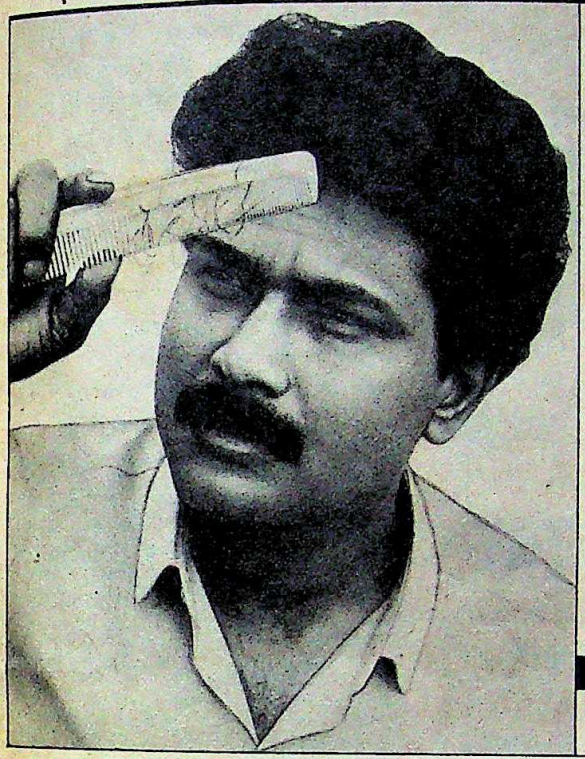

२५ साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के बाल झड़ रहे हैं....लेकिन उन्हें इसका पता नहीं!

क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आज ही यह परीक्षण कीजिए.
अपने बालों को ज़ोरों से कंघी कीजिए. अगर कंघी पर बाल उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं.

इसका हल है — प्योर सिल्विक्रिन
बालों के झड़ने का कारण है — ज़रूरी अमिनो एसिड्स की कमी — जो आपके बालों की कुदरती ख़ुराक हैं. केवल प्योर सिल्विक्रिन में ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है जो इस कमी को पूरा करता है.
इसके कारण है :

१. प्योर सिल्विक्रिन १७ अमिनो एसिड्स का अनोखा मिश्रण है — आपके बालों की कुदरती ख़ुराक.

२. रेडियो ट्रेसिंग का प्रयोग करने वाली विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि प्योर सिल्विक्रिन, बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी पहुँचती है, बालों में कुदरती ख़ुराक की कमी पूरी करती है और बालों को फिर से स्वस्थ बनाती है.

उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की त्वचा पर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का स्वास्थ्य सामान्य नहीं हो जाता.

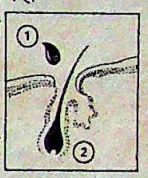

जल्दी कीजिए!
आज ही प्योर सिल्विक्रिन आज़माइए.

प्योर सिल्विक्रिन

OBM/1044/Hin M

डिजाइन-प्रतियोगिता

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अपने प्रतीक चिन्ह (लोगो) के रूप में उपयोग हेतु उपयुक्त डिजाइन आमंत्रित करता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल द्वारा चुनी गई डिजाइन को रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

संस्थान

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय , भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग का एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसकी परिकल्पना एक जैविक-पूर्ण तथा विकासमान आन्दोलन के रूप में की गई है। इस संग्रहालय में मानव की कहानी को काल एवं स्थान के परिप्रेक्ष्य में, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हुए भारतीय सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जायेगा। सामान्य मानव विज्ञान को केन्द्रीय विषय वस्तु मानकर यह संस्थान मुख्यतः निम्न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रीभूत होगा :

- मानव उद्विकास एवम् विभिन्नताएं
- प्रागैतिहासिक युग में संस्कृति एवम् समाज,
- सांस्कृतिक प्रतिमान (भारतीय संस्कृति की आधारभूत संपन्नता व विविधता)

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अपने उद्देश्यों को दो परिपूरक घटकों के माध्यम से प्राप्त करेगा :

- विस्तृत दीर्घाओं सहित आंतरिक संग्रहालय, तथा
- स्थायी मुक्ताकाश प्रदर्शनियों सहित बाह्य परिसर संकुल

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएँ इस प्रतियोगिता से सम्बन्धित निर्धारित प्रवेश-पत्र, नियम और उपनियम तथा अन्य जानकारी के विषय में **निदेशक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पोस्ट बेग नं. 7, ई-5, सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल, पिन-462 016.** से पत्राचार कर सकते हैं। यह अनुरोध इस विज्ञापन के प्रकाशन से एक माह तक ही ग्राह्य होंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए प्रवेश-पत्र जिसमें डिज़ाइन भी संलग्न हो इस विज्ञापन के प्रकाशन से ढाई माह की अवधि के अन्दर ही स्वीकार किये जायेंगे।

टिप्पणी: राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के कर्मचारी तथा भिन्न समितियों के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

Ad. No. RMS-1/88

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

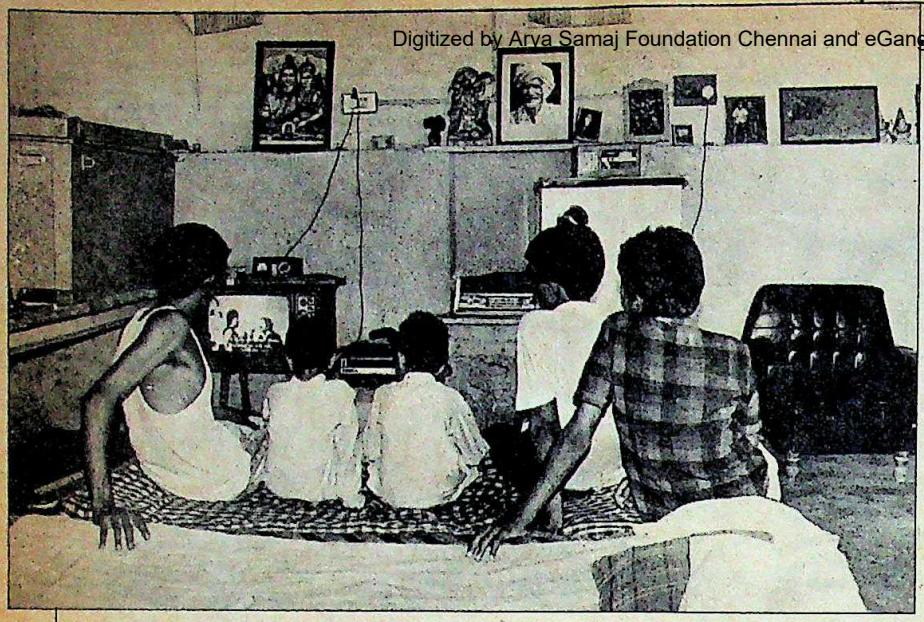

कंवर अपने बेटों के साथः पैसों की बरसात

गांव के नौजवान, जो पांच ही साल पहले तक पाजामा पहने गलियों में मटरगश्ती किया करते थे, अब जींस पहने नई खरीदी मोटर-साइकिल पर सवार होकर दनदनाते फिरते हैं. बहुतों को तो शराब और नशीली दवाओं की लत लग गई है. बड़े-बूढ़े देर रात को उन पार्टियों में मशगूल रहते हैं जिनमें अमूमन दिल्ली के वेश्यालयों से औरतें लाई जाती हैं.

बुजुर्ग लोग भी धनलोलुपता में किसी से पीछे नहीं रहे. अति दुखद पहलू तो यह है कि भोले-भाले गांववासियों पर, जो अक्सर फसल पर निर्भर रहा करते थे, नोटों की चकाचौंध का भारी असर हुआ. उनमें से किसी ने कहीं अन्यत्र जमीन में पैसा लगाने

सभी फोटो: भवान सिंह

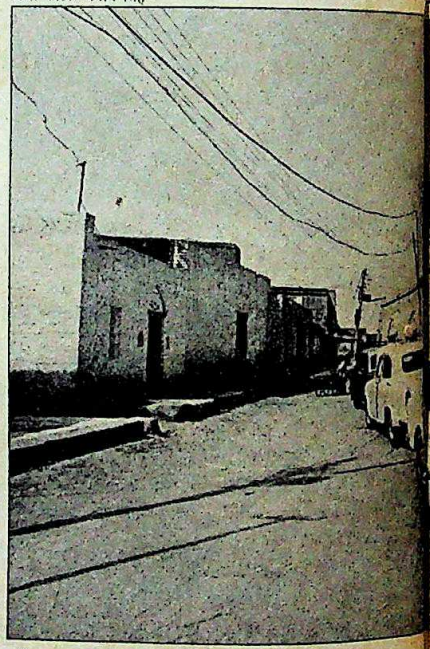

की बात भी नहीं सोची. नंगलदेवत के 40 वर्षीय प्रधान रामनारायण सेहरावत कहते हैं, "बमुश्किल 25 फीसदी गांववालों ने दुबारा जमीन खरीदने में पैसा लगाने की बाबत सोचा." कंवर कहते हैं, "हम किसी धंधे में पैसा लगाने वाले नहीं, पूरा पैसा मकान बनवाने और शादी-ब्याह में खर्च कर देते हैं."

कुछ साल पहले तक कंवर एक साधारण किसान थे. उनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत खेती की 42 एकड़ जमीन थी. आज वे गांव के ऐसे धनी परिवारों में से हैं जिनकी जमीन भवन निर्माताओं या सरकार ने खरीदकर उन्हें इतनी मोटी रकम थमा दी है जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखी. पैसे की एकाएक बरसात और शहरी जिंदगी की परेशानियों ने कंवर और उन सरीखे दूसरे लोगों को सामाजिक तौर पर ऐसी जगह ला

नंगलदेवत गांव

शहरी चकाचौंध का दुष्चक्र

अचानक आई समृद्धि के बोझ तले दम तोड़ती ग्रामीण संस्कृति

एक साल पहले योजना आयोग के सर्वेक्षणकर्ता दिल्ली में हरियाणा की सीमा से सटे नंगलदेवत गांव में कंवर सिंह के घर का मुआयना करने पहुंचे. वे ग्रामीणों की जीवन शैली का विवरण जुटाने निकले थे और उनके दिमाग में किसान की छवि पहले से ही अंकित थी. वे एक ऐसे मध्यमवर्गीय भोले-भाले जाट किसान से मिलने की उम्मीदें संजो रहे थे जिसके घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा हो, खेती के औजार आसपास बिखरे हों, बच्चे स्कूल जाने के बजाय लुका-छिपी खेल रहे हों और परिवार के मर्द या तो खेतों में जुटे हों या हाट-बाजार गए हों.

लेकिन सर्वेक्षणकर्ताओं को वहां के हालात देखकर झटका-सा लगा. कंवर सिंह के पास खेतीबाड़ी के लिए बिलकुल भी जमीन नहीं थी. उनके पास थी तो एकदम नई कार और चमचमाती मोटरसाइकिल जो उनके नए बने गैरेज में खड़ी थीं. खेतों में जुटे होने के बजाय 30 वर्षीय कंवर अपने वीडियो पर एक हिंदी फिल्म देख रहे थे. शराबी के रूप में कुख्यात उनके 26 वर्षीय भाई कुलदीप ने अपने कमरे से बाहर आने से ही इनकार कर दिया जहां वह ज्यादातर वक्त पिनक में पड़ा रहता है. आसपास कहीं कोई बच्चा नहीं दिख रहा था. वे शहर के एक स्कूल में पढ़ने गए थे.

नंगलदेवत (जनसंख्या 6,500) के सभी घरों की अमूमन यही कहानी है. यह गांव भारत में हो रही उस सामाजिक उथल-पुथल का प्रतीक है जो शहरी-ग्रामीण अंतर को अचानक पाटने से पैदा होती है.

अति दुखद पहलू तो यह है कि उन भोले-भाले गांववासियों पर, जो फसल पर निर्भर रहा करते थे, नोटों की चकाचौंध का भारी असर हुआ. उनमें से किसी ने कहीं अन्यत्र जमीन में पैसा लगाने की बात भी नहीं सोची

1963 और 1986 के बीच सरकार ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार की खातिर इस गांव की जमीन अधिग्रहीत की थी. गांववालों की समस्त 68 एकड़ रिहायशी और 2,082 एकड़ खेती वाली जमीन अब सरकारी संपत्ति हो गई है. रातोरात करीब 400 जाट परिवारों को एक साथ मुआवजे के 10 करोड़ रु. दिए गए.

इसका नतीजा नाटकीय तो है ही और बहुत हद तक दुखद भी. गांव का सांस्कृतिक ताना-बाना पैसे के बोझ तले चरमरा गया है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खड़ा किया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है.

यह नंगलदेवत की स्थिति का भी एकदम सही प्रतीक है. इसके एक ओर चकाचौंध करने वाला पांच सितारा होटल है तो दूसरी ओर उतने ही ठाटबाट वाला इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा. पूरा गांव ऊंचे-ऊंचे टीवी एंटीना से अटा पड़ा है. यहां पक्की सड़कें तो नहीं हैं मगर 100 से ज्यादा कारें हैं. बिजली दिन में आठ घंटे ही आती है लेकिन तकरीबन हर घर में एक वीडियो और वैभव के प्रतीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं. नल शायद यहां एक भी न हो (ज्यादातर घरों में हैंड पंप हैं) पर अब पियक्कड़ों की भरमार है. इस इलाके के दो बैंकों के खातों में करोड़ों रु. जमा हैं लेकिन बेरोजगार घर-घर में हैं. दिल्ली

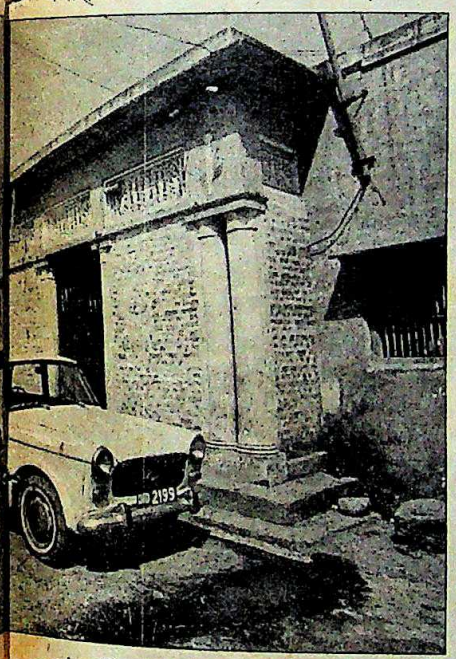

गांव की एक गली; और (नीचे) ताश खेलते हुए बड़े-बूढ़े: करने को है ही क्या

की उपभोक्ता संस्कृति ने यहां कहर ढा दिया. ग्रामसभा के 72 वर्षीय सदस्य बसंता कहते हैं, "दिल्ली जाने वाला कोई नौजवान हर बार कोई नई चीज साथ लिये लौटता है."

पैसे की बाहरी चमक-दमक के फंदे के बावजूद नंगलदेवत के बहुत से लोग महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने भविष्य का कतई ख्याल नहीं रखा. वे अपनी इस दुर्दशा का जिम्मेदार अब सरकार को ठहराते हैं. उनकी शिकायतों का कोई अंत नहीं. मसलन मुआवजा इतना कम था कि उससे मिला पैसा कहीं और नहीं लगाया जा सका, भुगतान मिलने तक जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी थीं, किसी ने यह नहीं बताया कि पैसे पर कर भी लगता है वगैरह-वगैरह.

निश्चय ही नंगलदेवत को महानगर से जोड़े जाने से कई गांववासी तबाही की राह पर आ खड़े हुए हैं. कंवर सिंह का भाई कुलदीप इसका सटीक उदाहरण है. जब उसके पिता की 42 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया तो दोनों भाइयों को 2.5-2.5 लाख रु. मिले. कुलदीप ने अपना आधा हिस्सा तो उड़ा दिया और बाकी बैंक में जमा करा दिया. लेकिन उसका खाता जाम कर दिया गया क्योंकि कुलदीप ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे कर भी अदा करना है. वह अपने जमा धन के ब्याज से परिवार का खर्चा चलाता है. नंगलदेवत में न्यू बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक एस.एल. हरित का कहना है कि उनकी शाखा में कम-से-कम 200 खाते जाम कर दिए गए हैं.

गांववासी अब आराम की ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं. यहां के बुजुर्ग लोग अपना वक्त ताश खेलने में बरबाद करते हैं. पूर्व प्रधान रामनारायण के घर के बाहर ताश खेल रही एक टोली ने एक स्वर में बताया, "साल के इस वक्त (कटाई के मौसम में) भी गांव में कोई मर्द नहीं है. अब तो हमने काम न करना सीख लिया है." युवाओं को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें शिकायत है कि सरकार ने वैकल्पिक नौकरी पाने में उनकी कोई सहायता नहीं की. दिल्ली प्रशासन के एक अधिकारी का इस पर जवाब था, "हमारी जिम्मेदारी तो मुआवजा अदा करने के साथ ही खत्म हो गई."

बेकारी और आसानी से मिले पैसे की वजह से गांव के बहुत से नौजवान दुराचार में फंस गए. मुआवजे के चेक के साथ-साथ मादक दवाएं खासकर ब्राउन शुगर और स्मैक भी आईं. चार साल पहले यहां नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित था. अब ज्यादातर नौजवान नशीली दवाओं के आदी हो गए हैं. सेहरावत कहते हैं, "अब कम-से-कम 30 फीसदी लोग, खासकर नौजवान नशीली दवाएं लेते हैं. अमूमन हर गांववासी यह बात जानता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता."

नशीली दवाएं काफी महंगी होने के कारण बहुत से नशाखोरों ने इस लत को पूरा करने के लिए मुआवजे का अपना पैसा फूंक दिया है. एक बैंक कर्मचारी का कहना है, "यहां हालत बेहद खराब है. मैं खुद ऐसे लोगों को भुगत चुका हूं जिन्होंने अपनी लत पूरी करने के लिए एक साल में 20 से 25 हजार रु. निकलवाए हैं." तेजी से पैसा खर्च होने की वजह से कुछ नशाखोर बेहद निराशा के शिकार हो गए. गांव के कम-से-कम चार लोगों ने इसी वजह से आत्महत्या कर ली. नशीली दवाओं की लत बढ़ने के साथ-साथ अपराध भी बढ़े हैं. उदास सेहरावत कहते हैं, "युवा पीढ़ी तो एकदम बिगड़ गई है."

इसकी एक वजह यह हो सकती है कि नंगलदेवत के नौजवानों के पास अपना भविष्य संवारने के लिए कुछ नहीं बचा है. हवाई अड्डे के विस्तार का काम ज्यों-ज्यों समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, गांववासी जान गए हैं कि उन्हें वहां से खदेड़े जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. सरकार से वैकल्पिक आवासीय जमीन और मुआवजे की सौदेबाजी अभी जारी है. जल्दी ही नंगलदेवत गांव का अस्तित्व मिट जाएगा. और इसी के साथ पिछले कुछ वर्षों की रंगरेलियों का अंत भी हो जाएगा, जिसकी उम्मीद थी भी.

—पंकज पचौरी

CC-0. I Gurukul Ka

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूरदर्शन

दावों की कलई खुली

बंबई हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति के अधिकार पर जोर दिया

बंबई उच्च न्यायालय के एक ताजा फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकारी समाचार माध्यमों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं है, दूरदर्शन भले ही अपनी छवि एक खुले संस्थान की बनाने की जद्दोजहद में लगा हो. एक ऐतिहासिक फैसले में न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर ने एक वकील इंदिरा जयसिंह के विचार काट-छांटकर पेश करने के लिए दूरदर्शन की खिंचाई की है. जयसिंह ने ये विचार मुस्लिम महिला विधेयक पर मार्च 1986 में दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में प्रकट किए थे. जयसिंह की याचिका पर फैसला देते हुए न्यायमूर्ति मनोहर ने दूरदर्शन को निर्देश दिया है कि वह आगे जब भी इस विषय पर कोई कार्यक्रम दिखाए तो उसमें जयसिंह को जरूर शामिल करे.

विवादास्पद मुस्लिम महिला विधेयक फरवरी 1986 में संसद में पेश किया गया था और पूरे देश भर में बहस शुरू हो गई थी. दूरदर्शन ने अपने 'सच की परछाईं' कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित कानूनों को मुद्दा बनाया था. जयसिंह का इंटरव्यू दूरदर्शन के बंबई स्टुडियो में रिकार्ड किया गया. छह मिनट के इंटरव्यू में जयसिंह ने इस विधेयक (अब कानून) का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक, महिला विरोधी और औरतों के प्रति गैर-बराबरी वाला बताया था.

दो दिन बाद 3 मार्च '86 को जब यह कार्यक्रम दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में दिखाया गया तो जयसिंह यह देखकर सकते में आ गईं कि उस विधेयक के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था वह इस इंटरव्यू से निकाल दिया गया था.

दूरदर्शन मुख्यालय मंडी हाउस में विरोध दर्ज कराने पर वहां से चलताऊ जवाब मिला कि समय की कमी और विधेयक पर संसद में चल रही बहस की वजह से विधेयक का जिक्र ही कार्यक्रम से हटा दिया गया. इस जवाब से असंतुष्ट जयसिंह ने एक याचिका दायर कर दी कि दूरदर्शन ने इंटरव्यू को काटकर अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का हनन किया है.

सभी फोटो तारक भोजानी

जयसिंह (ऊपर) और न्यायमूर्ति मनोहर: ऐतिहासिक फैसला

न्यायमूर्ति मनोहर ने दूरदर्शन का कोई भी तर्क नहीं माना. उन्होंने कहा कि समय की कमी की वजह से किसी एक पूरे विषय को ही निकाल दिया जाना सही नहीं ठहराया जा सकता. और संसद में चल रही बहस की वजह से विवादास्पद विधेयक पर व्यक्त विचारों को काटने से साफ हो जाता है कि यह सेंसरशिप थी. न्यायमूर्ति को सबसे ज्यादा हैरत दूरदर्शन के वकील के इस तर्क पर हुई कि अभिव्यक्ति की आजादी टेलीविजन पर नहीं दी जा सकती क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19 टेलीविजन के कार्यक्रमों पर लागू नहीं होता. न्यायमूर्ति ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी की जितनी रक्षा कहीं और करता है उतनी ही टेलीविजन पर भी. दूरदर्शन के वकील के तर्क को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसके महानिदेशक भास्कर घोष कहते हैं, "दूरदर्शन किसी भी तरह संविधान के दायरे से बाहर नहीं है."

बहरहाल, इस फैसले ने अब इस बात की गुंजाइश बना दी है कि दूरदर्शन का कोई प्रोड्यूसर अगर किसी के विचार महज इसलिए काट देता है कि वे सत्ता पक्ष को नागवार गुजरेंगे तो दूरदर्शन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

वास्तव में उधर जयसिंह की याचिका पर सुनवाई चल रही थी कि दूरदर्शन एक और विवाद में फंस गया. यह विवाद विनोद दुआ के कार्यक्रम 'आजकल' में बोफोर्स तोप पर जनरल मायादास की टिप्पणियों के संपादन के सिलसिले में है. जनरल मायादास का कहना है कि इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि वे दूसरी तोप के पक्ष में थे. लेकिन दूरदर्शन ने इस बयान को पूरी तरह से उड़ाकर उनके विचारों को गलत ढंग से पेश किया. जयसिंह कहती हैं, "दूरदर्शन को इस सिलसिले में नीति निर्देश तय करने होंगे कि जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, निर्माता उनके नजरिये को किस तरह पेश करें."

जयसिंह के लिए मुद्दा सेंसरशिप का ही नहीं है. उनके सामने सवाल यह है कि क्या जनता टेलीविजन जैसे सशक्त माध्यम को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बना सकती है. मुस्लिम महिला कानून के बारे में अपने विचार दूरदर्शन पर व्यक्त करने के अधिकार का उपयोग करने के लिए वे एकदम कृतसंकल्प दिखती हैं. बहरहाल, उनके इस मुकदमे ने दूरदर्शन के इस दावे की कलई तो खोल ही दी है कि वह अभिव्यक्ति का एक खुला मंच है.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेखा और नसीर: बेजोड़ अभिनय

इजाजत

बीते कल की यादें

अरसे बाद आई 'बीच' की एक बंबइया फिल्म

लता मंगेशकर ने जब अपनी पहली फिल्म 'लेकिन' के निर्देशन का जिम्मा गुलज़ार को सौंपा तो बंबई की अनेक फिल्मी हस्तियों ने हैरानी जाहिर की थी. अच्छी कहानी और स्वस्थ मनोरंजन वाली 'बीच' की फिल्मों का जमाना लगभग एक दशक पहले ही गुजर चुका है. अब तो गुलज़ार-हृषिकेश मुकर्जी के उस दौर के बाद तेज हुई कला सिनेमा की लहर भी दम तोड़ने जा रही है. और तो और, सात-आठ साल में गुलज़ार की जो भी फिल्म रिलीज हो सकी वह चल नहीं पाई. रिलीज भी हुई तो बस एक आध ही जगह. (राजधानी में रिलीज होने वाली उनकी पिछली फिल्म 'अंगूर' थी जिसे चार साल हो गए). इस कदर पिछड़े हुए गुलज़ार पर लता मंगेशकर ने इतना भरोसा कैसे कर लिया? पिछले पखवाड़े रिलीज हुई उनकी फिल्म 'इजाजत' कुछ हद तक इस भरोसे के कारणों को रेखांकित करती है.

एक रेलवे स्टेशन पर रात को एक मुसाफिर उतरता है. उसे कहीं आगे जाना है. लेकिन अगली सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं. वह रात गुजारने वेटिंग रूम पहुंचता है जहां पहले से एक महिला मौजूद है. मुसाफिर उसे देखकर अवाक् रह जाता है. वह महिला पांच साल पंहले उसकी प्रेमिका की वजह से घर छोड़कर चली गई उसकी पत्नी है. उसकी ट्रेन भी अगली सुबह है. वह तूफानी रात वे दोनों वेटिंग रूम में अकेले गुजारते हैं. इन पांच सालों में सब कुछ बदल गया है लेकिन साझी यादें उन्हें फिर से अतीत में ले जाती हैं. वे फिर पति-पत्नी की तरह ही एक दूसरे को झिड़कने, ताने देने, एक दूसरे पर अधिकार जताने और एक दूसरे की मदद करने लगते हैं. एक रात के लिए उस सुनसान स्टेशन का वेटिंग रूम जैसे घर में बदल जाता है. नायक एक जगह कहता है, "जिंदगी भी वेटिंग रूम ही तो है." वास्तव में वेटिंग रूम कहानी के हर पात्र की नियति का प्रतीक है. हर पात्र मानो उस ट्रेन का इंतजार कर रहा है जो उसे सही जगह पहुंचा दे. लेकिन इंतजार जारी रहता है. कोई सही ट्रेन नहीं आती.

फ्लैश बैक में चलने वाली कहानी में मुख्य पात्र हैं—नायक (नसीर), उसकी पत्नी (रेखा) और उसकी प्रेमिका (अनुराधा पटेल). मजबूरन नायक को शादी करनी पड़ती है. पत्नी जानती है कि पहले वह अपनी प्रेमिका के साथ रहा करता था. नायक प्रेमिका को भुलाने की कोशिश करता है. लेकिन घर के कोने-कोने में उसकी यादें टंकी रह गई हैं. उसे दीवानावार चाहने वाली प्रेमिका उससे दूर रहने की कोशिश भी नहीं करती. वह तो उसकी पत्नी से भी मिलना चाहती है. लेकिन पत्नी इसके लिए तैयार नहीं. उसे प्रेमिका से हमदर्दी है लेकिन वह अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती. प्रेमिका का पागलपन बढ़ता देख पति उसे पत्नी से मिलाने की ठान लेता है. लेकिन उस दिन न प्रेमिका उसे मिली और जब वह घर लौटा तो पत्नी भी नदारद. "जो सच है और जो सही है" पर चलने वाली पत्नी घर छोड़कर जा चुकी है. फिर वे पांच साल बाद वेटिंग रूम में ही मिलते हैं. नायक बताता है कि इस बीच प्रेमिका मर चुकी है.

रात खत्म होती है. शायद ट्रेन आने वाली है. नायक सामान बांधने लगता है. तभी दूसरा पति (शशि कपूर) पत्नी को लेने आ पहुंचता है. पत्नी नायक के पांव छूकर दूसरे पति के साथ वेटिंग रूम से बाहर निकलती है. ठगा सा नायक भी धीरे-धीरे बाहर आता है. पत्नी मुड़कर उसे देख रही है. शॉट यहीं फ्रीज हो जाता है. इंतजार कभी खत्म नहीं होता.

पति की दुखी और तनहा रह गई प्रेमिका से सहानुभूति रखने वाली लेकिन पति के मन और घर में बात-बात में उभरने वाली उसकी यादों को बर्दाश्त न कर पाने वाली पत्नी के रूप में रेखा के लिए यह एक और खूबसूरत फिल्म है. लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं नसीर. पत्नी और प्रेमिका में बंटे व्यक्ति का द्वंद्व उनके चेहरे से बखूबी टपकता है.

अनुराधा पटेल के लिए यह शायद पहली महत्वपूर्ण फिल्म है. लेकिन उनके बेहद संवेदनशील, नज्म लिखने वाले, मगर बचपने से भरे चरित्र को उभारने में शायद गुलज़ार को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है.

यों भी परदे के पीछे से गुलज़ार कदम-कदम पर अपना अहसास कराते हैं. गीत, संवाद, कहानी तो उनकी है ही. अपनी नज्मों के इस्तेमाल का मोह वे यहां भी नहीं छोड़ पाए. नायक की शादी के बाद पहली बार प्रेमिका का उससे फोन पर बतियाने वाला दृश्य झिझोड़ कर रख देता है. यह गुलज़ार की निर्देशन प्रतिभा का कमाल है. कई प्रतीक भी खूबसूरती से पेश किए गए हैं. मसलन पत्नी के घर से जाने के बाद अलमारी के भीतर टंगे ढेर से खाली हैंगर.

रेखा और गुलज़ार के बीच कुछ अनबन के कारण इस फिल्म की शूटिंग कई महीने रुकी रही थी. बाद में फिल्म पूरी भी हुई तो एक लंबे अरसे बाद थिएटर तक पहुंच पाई. यह फिल्म चाहे 'मेरे अपने', 'परिचय', 'कोशिश', 'आंधी' और 'मौसम' को टक्कर न देती हो, मगर गुलज़ार के टीवी सीरियल 'मिर्ज़ा गालिब' और फिल्म 'लेकिन' के लिए इंतजार की शिद्दत जरूर बढ़ा देती है. साथ ही 'इजाजत' एक तरह की खीज भी पैदा करती है कि अच्छे सिनेमा के लिए कोई समानांतर वितरण व्यवस्था क्यों नहीं शुरू की जाती?

—शीलू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वृत्तचित्र

संकल्पवान शूरवीरों का संघर्ष

विदेशों में प्रशंसित वृत्तचित्र निर्माता अपने ही देश में उपेक्षित

भारत के वृत्तचित्र निर्माताओं की मुसीबत यह है कि लोग यह तो चाहते हैं कि वृत्तचित्र जरूर बनें लेकिन वे वृत्तचित्रों को देखना पसंद नहीं करते. वृत्तचित्र के नाम पर लोग सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाए जाने वाले फिल्म डिवीजन के उबाऊ वृत्तचित्रों को ही जानते हैं. पर्यावरण जैसे विषयों पर वृत्तचित्र बनाने वाले तेजबीर सिंह कहते हैं, "सरकारी वृत्तचित्र बोर करने लगते हैं."

लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद स्वतंत्र वृत्तचित्र निर्माताओं की एक पूरी पीढ़ी सक्रिय रही है. ये गुमनाम 'शूरवीर' उन विषयों पर वृत्तचित्र बना रहे हैं जिनका जिक्र आते ही फिल्म डिवीजन की शायद कंपकंपी छूटने लगे. इनमें से ही एक, रमेश शर्मा कहते हैं, "वृत्तचित्रों के निर्माता हमेशा से ही असहमति की आवाज बुलंद करते रहे हैं."

इन निर्माताओं की कठिनाइयों का अंत नहीं है. पैसे की कमी है, और साधनों की भी. और सेंसर बोर्ड है कि हमेशा यमदूत की तरह सामने खड़ा रहता है. एक निर्माता कहते हैं, "हम बहुत पैना और खूब शोधपरक वृत्तचित्र बना भी लें तो दिखाएंगे कहां?" अपने देश में इन निर्माताओं की भले ही पूछ न हुई हो लेकिन इनमें से कइयों को अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. कइयों के वृत्तचित्र यूरोपीय और अमेरिकी टेलीविजन कंपनियों ने खरीदे हैं.

दरअसल इस विधा की ताकत की पहचान अभी अपने यहां हो नहीं पाई है. यह पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम बन सकता है. इसके जरिये कोई खोजपूर्ण खबर बेहद रोचक ढंग से पेश की जा सकती है, उन स्थानों से परिचित कराया जा सकता है जहां कई लोग शायद कभी न जा पाएं और आम तौर पर अनसुने कर दिए जाने वाले स्वरों को जोरदार बनाया जा सकता है. इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वृत्तचित्र 'भोपाल: वियांड जेनोसाइड' के निर्माता तपन बोस कहते हैं, "यह एक नई लड़ाई है. भारत में स्वतंत्र वृत्तचित्रों का आंदोलन कायम रहेगा. हम अब इसकी अनदेखी नहीं कर सकते."

ये संकल्पवान योद्धा दो कारणों से पैर जमाते जा रहे हैं. एक, लोग अब कथित विकास की दिशा और इसकी उपलब्धियों या नाकामियों पर उंगली उठाने लगे हैं. और दूसरा यह कि दूरदर्शन के उदारवाद के कारण इन्हें लगने लगा है कि यह उनके अपने वृत्तचित्रों को प्रदर्शित करने का माध्यम बन सकता है. अनेक महत्वपूर्ण वृत्तचित्रों को अभी भी दर्शकों की तलाश है.

■ तीन साल पहले आनंद पटवर्धन ने बंबई के फुटपाथवासियों पर एक वृत्तचित्र 'हमारा शहर' बनाया था. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने इसके बारे में लिखा, "यह भारत में बना आज तक का सबसे बेहतरीन वृत्तचित्र है." भारत में फिल्म क्लबों और मजदूर संघों ने इसे हजारों बार अपने यहां दिखाया. आज भी इसे बंबई में हफ्ते में दो बार कहीं न कहीं दिखाया जाता है लेकिन दूरदर्शन ने इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया.

'हमारा शहर' एक अद्वितीय वृत्तचित्र है. इसमें व्यवस्था के खिलाफ वास्तविक गुस्सा है. झोंपड़पट्टी सफाई कार्यक्रमों का खौफ फुटपाथवासियों पर हमेशा तारी रहता है. पटवर्धन फिल्म में नगर निगम आयुक्त से इस मामले पर बात करते हैं. पर उनका कैमरा आयुक्त के चेहरे पर नहीं है. वह उनके विशाल बंगले, हरे-भरे लॉन, हवा के मंद झोंकों में लहराती फूलों की डालियों पर सरकता जाता है. इस दृश्य को ऐसे फिल्माया

आनंद पटवर्धन; और उनकी फिल्म *हमारा शहर* में फुटपाथवासी

"मुझे खुशी है कि इन फिल्मों से काफी पैसा नहीं बन पाता. अन्यथा लोग गलत फिल्मों का निर्माण करते"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वन्यजीवन पर फिल्म बनाने वाले नरेश बेदी और उनका एक *नरभक्षी*

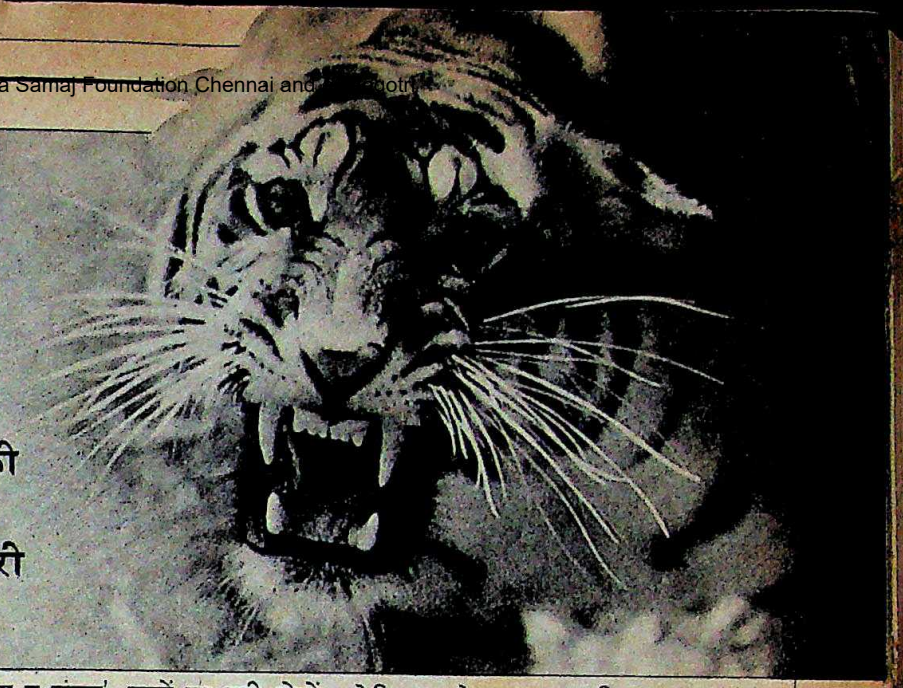

दूरदर्शन कार्यालय जाना समय की बरबादी है. मंडी हाउस में अक्सर यही सुनने में आता है कि अधिकारी किसी बैठक में व्यस्त हैं''

गया है कि यह पहले दृश्य का बिलकुल विरोधाभास लगे जिसमें फुटपाथवासी मृत बच्चे को चटाई में लपेटकर दफनाने ले जा रहे हैं.

इसी वृत्तचित्र का एक और दृश्य: एक फुटपाथवासी पांच साल की अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता है. उसे जवाब मिलता है, ''हम फुटपाथ के पते को मंजूर नहीं करते.'' इस पर निगम आयुक्त को बुदबुदाते हुए दिखाया जाता है, ''वे जहां से आए हैं उन्हें वहीं लौट जाना चाहिए.'' पटवर्धन पूछते हैं, ''कौन-सी जगह है वह?''

'हमारा शहर' को 1985 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. पटवर्धन ने एक फुटपाथवासी स्त्री को पुरस्कार लेने के लिए भेज दिया. लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद उसका घर एक बार फिर उजाड़ दिया गया.

पटवर्धन 'हमारा शहर' को दूरदर्शन पर दिखाए जाने की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने समर्थन में सत्यजीत राय और मृणाल सेन समेत 200 प्रमुख भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर जुटाए.

■ इसी तरह नरेश बेदी के वृत्तचित्रों को देश भर में क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए इसका कोई कारण समझ में नहीं आता. दुनिया भर में वन्यजीवन पर फिल्म बनाने वाले बेहतरीन निर्माताओं में वे गिने जाते हैं. वन्यजीवन जैसे दुरूह विषय पर भी वे मार्मिक और बेहतरीन फिल्में बनाते हैं. उनकी एक ही फिल्म 'घड़ियाल' दूरदर्शन पर दिखाई गई है. इस फिल्म पर बेदी को ब्रिटेन में 'बेस्ट वाइल्डलाइफ कैमरामैन' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

पिछले नवंबर में बेदी ने बीबीसी के चैनल चार के लिए तीन वृत्तचित्र बनाए—'सेविंग द टाइगर', 'मैनईटर्स ऐंड एलीफैंट' और 'लॉर्ड ऑफ द जंगल'. बाघों पर बनी दोनों फिल्मों को इस साल मार्च में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कारों के लिए नामजद किया गया. 'सेविंग द टाइगर' फिल्म के लिए बेदी ने अपने एरिफ्लेक्स कैमरे के साथ एक बाघिन और उसके चार शावकों के पीछे चार साल बिताए. जंगल के वातावरण में एक तरह की गरमी है. चौकन्ने होकर इधर-उधर ताकते हिरण-झुंड के चेहरे आतंकित हैं. कामातुर बाघिन अपने साथी को बुलाने के लिए मधुर गर्जन करती है और एक पेड़ से अपने शरीर के घर्षण के द्वारा हवा में एक विशेष महक फैला देती है. बाघों की रतिक्रिया पहली दफा कैमरे में बंद की जाती है. और बेदी उनसे मात्र 30 फीट की दूरी पर से यह सब फिल्माते हैं. उसके बाद वे बाघिन के प्रसव और शावकों के जन्म को फिल्माते हैं. और फिर उन शावकों के खेल की आक्रामक भंगिमाओं को. फिल्म में व्याघ्र-शावक के जन्म से लेकर जवान होने तक के दृश्य हैं.

दुर्भाग्य यह है कि ऐसी प्रतिभाओं की भारत में कोई कद्र नहीं होती. पिछले साल 22 दिसंबर को बेदी ने अपनी फिल्मों को प्रेसवालों को दिखाया. उन्होंने इस प्रदर्शन में दूरदर्शनवालों को भी निमंत्रण भेजा. लेकिन दूरदर्शन के एक भी अधिकारी ने आने की जरूरत महसूस नहीं की. बेदी कहते हैं, ''वहां जाना सिर्फ समय की बरबादी है. मंडी हाउस में अक्सर यही सुनने में आता है कि अधिकारी किसी बैठक में व्यस्त हैं.''

■ पटवर्धन की तरह ही दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता तपन बोस और सुहासिनी मुले के वृत्तचित्र 'भोपाल: बियांड जेनोसाइड' (भोपाल: हादसे के बाद) को इस साल मार्च में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया. लेकिन उनसे साफ कह दिया गया, ''हम इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते. हमारे पास 16 मिमी का प्रोजेक्टर नहीं है.'' इस व्यवहार से नाराज होकर बोस और मुले ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और फिल्म समारोह निदेशालय से कहा कि वह इस पैसे से अपने लिए एक प्रोजेक्टर खरीद ले. इस रवैये से क्षुब्ध एक फिल्म निर्माता ने कहा, ''यदि कोई फिल्म पुरस्कृत होती है तो उसे प्रदर्शित करना ही चाहिए.''

भोपाल उन कुछ भयावह त्रासदियों में से एक है जो शांतिकाल में भी हिरोशिमा में हुए मौत के तांडव का एहसास कराती है. मुले और बोस हादसे के तीन दिन बाद वहां फिल्म बनाने पहुंचे थे. फिल्म में 'मिक' (मिथाइल आइसोसाइनेट) गैस रिसने की बारीकी से पड़ताल की गई है. इस वृत्तचित्र की ताकत यह है कि इसमें कैमरा हर घटना को जैसे तुरत कैद कर लेने को सही वक्त पर हाजिर दिखता है. भोपाल शहर लाशों के ढेर में बदल रहा था. फिल्म में कथावाचक कहता है, ''पूरे शहर पर हत्यारे की साया मंडरा रही है. अपनी ही सरकार ने लोगों से दगा किया.''

बोस कुछ अनूठे दृश्य फिल्माने में कामयाब हुए हैं. हमीदिया अस्पताल के बाहर शवों का ढेर हो या सरकारी प्रेस कांफ्रेंस, जिसमें 'सरकार ने पहले ही अपनी धारणा स्पष्ट कर दी थी कि मिक गैस का कोई दूरगामी असर नहीं होने वाला है', हर बात पर फिल्म सवालिया निशान लगाती है. अंतिम दृश्य तो मानसपटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है. यह दृश्य सांस लेने की कोशिश करती एक मासूम बच्ची का है. जिसकी मृत्यु उसके जन्म के 18वें दिन ही हो जाती है.

'भोपाल: हादसे के बाद' एक ऐसी फिल्म है जिसे प्रदर्शित करने से दूरदर्शन हमेशा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बचना चाहेगा. लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सभी फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाने के सरकारी फैसले के बाद इस फिल्म को भी अनचाहे ही दिखाना पड़ सकता है.

■ 'द मीडियास्टॉर्म' ग्रुप की लड़कियां शायद देश की सबसे कम उम्र की वृत्तचित्र निर्माता हैं. मुस्लिम महिला विधेयक पर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'इन सेक्युलर इंडिया' (धर्मनिरपेक्ष भारत में) बनाई तब उनकी उम्र मात्र 22 साल थी. फिल्म के पहले प्रदर्शन में हाल खचाखच भरा हुआ था. सैयद शहाबुद्दीन भी उसे देखने आए थे. लेकिन वे गुस्से से बीच में ही उठकर चले गए. इस फिल्म को सेंसर का प्रमाणपत्र नहीं मिला लिहाजा यह अभी तक डिब्बे में ही बंद है.

सती पर *फ्रॉम द बर्निंग एंबर्स* फिल्म बनाने वाली 'द मीडियास्टॉर्म' की लड़कियां

फिल्म को पूरा करने में नौ महीने लग गए. लिहाजा समय पर प्रदर्शित नहीं हो पाई''

पिछले महीने 'मीडियास्टॉर्म' ने एक दूसरी फिल्म 'फ्रॉम द बर्निंग एंबर्स' (जलती चिता से) भी बना डाली. जब इन लोगों ने रूपकंवर के सती होने की खबर सुनी तो पांचों लड़कियों ने मिलकर 1000-1000 रु. चंदा किया और दिवराला जा पहुंचीं. तमाम तनावों के बावजूद वे चुनरी महोत्सव को फिल्माने में कामयाब रहीं. सबीना गड़िहोके बताती हैं कि जब उन्होंने एक त्रिशूल पर रूपकंवर की चुन्नी लिपटी हुई देखी तो उन्हें लगा "जैसे मैं शताब्दियों पीछे के दौर में पहुंच गई हूं." लेकिन उन्हें अपने साहस की कीमत भी चुकानी पड़ी. दिवराला में इन लड़कियों को 45 लोगों ने पकड़ लिया और उन्हें एक कमरे में ले गए. वहां उन्होंने उनसे कहा, "हमारी भी हिटलिस्ट होती है." 'मीडियास्टॉर्म' की ही रंजनी मजूमदार कहती हैं, "हमने अपने सिर पर पल्लू डाला और बहाना बनाया कि हम भी सती समर्थक श्रद्धालु ही हैं."

उन्होंने हिंदू कट्टरतावाद के सबसे वीभत्स रूप को कैमरे में कैद करने में सफलता पाई है. यह फिल्म भी तकनीकी रूप से बहुत श्रेष्ठ नहीं है लेकिन इससे साहस और सामाजिक रोष का भरपूर एहसास होता है. गड़िहोके कहती हैं, "हमारे पास पैसे की कमी थी. सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि फिल्म को पूरा करने में नौ महीने लग गए, अन्यथा फिल्म तभी प्रदर्शित की जा सकती थी जब मामला गरम था."

फिल्म तैयार होने के बाद 'मीडियास्टॉर्म' की लड़कियों ने खुद ही इसके पोस्टर बनाए और फिल्म को सेंसर के हाथ में जाने से पहले उन्होंने इसे पत्रकारों, वकीलों और शिक्षाविदों को दिखाया.

■ वृत्तचित्र निर्माता मीरा दीवान तो हताश होकर कनाडा ही चली गईं. दहेज प्रथा पर उनकी पहली ही फिल्म 'गिफ्ट ऑफ लव' (प्यार का तोहफा) को आठ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले. ओबेरहॉसन के प्रतिष्ठित समारोह के चार जूरियों ने उनकी फिल्म को 400 फिल्मों में से पुरस्कार के लिए चुना. इन पुरस्कारों से चकित होकर दीवान कहती हैं, "मुझे लगा कि इन पुरस्कारों को लेकर मैं धोखाधड़ी कर रही हूं. मुझे सिर्फ रीता का ख्याल आ रहा था. अस्पताल में मैंने उससे इंटरव्यू लिया था. मुझे लगा कि मैं उसकी पीड़ा को भुना रही हूं."

उन्होंने दूसरी फिल्म फिरोजाबाद के काच कारखानों के बाल मजदूरों पर बनाई. भट्ठियों में इन बच्चों के पैर जल जाते हैं. और कइयों के घाव पक भी जाते हैं. मीरा दीवान कहती हैं, "इन आठ साल के बच्चों को देखकर मन द्रवित हो उठता था." जब इस फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाया गया तब 'ईव्स वीकली' ने लिखा, "इसे देखकर कांच की चूड़ियों को तोड़ डालने का मन होता है. इन्हीं के कारण उन बच्चों का जीने का हक छिन गया है."

दीवान की ताजा फिल्म 'इन द डस्ट ऑफ डेवलपमेंट' (विकास के गर्दो-गुबार तले) को दूरदर्शन ने इस बिना पर नकार दिया कि इसमें कोई हल नहीं सुझाया गया है. इससे निराश होकर वे कनाडा चली गईं.

तपन बोस; और उनकी *भोपाल: बियांड जेनोसाइड* का एक दृश्य

यह एक नई लड़ाई है. भारत का स्वतंत्र वृत्तचित्र आंदोलन कायम रहेगा. हम इसकी और उपेक्षा नहीं कर सकते''

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Ch... gotri

मीरा दीवान और उनकी ताजा फिल्म *इन द डस्ट ऑफ डेवलपमेंट* का एक दृश्य

वे तो आप को यह एहसास करा देते हैं कि मानो आपने अपने देश को ही बेच खाया हो''

वे कहती हैं, "वे तो आपको यह एहसास करा देते हैं कि आप देशभक्त ही नहीं हैं, मानो आपने अपने देश को बेच खाया हो."

■ लेकिन इधर ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि दूरदर्शनवाले प्रायश्चित कर रहे हों. मसलन 1 अप्रैल से वृत्तचित्रों की दर तिगुनी कर दी गई है, निर्माताओं को हर हफ्ते अहम समय पर आधा घंटा देने का आश्वासन दिया गया है और नौ वृत्तचित्र धारावाहिकों को मंजूरी दी गई है. भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ के अध्यक्ष मनमोहन शेट्टी कहते हैं, "आप और अधिक क्या चाहते हैं? दूरदर्शन अपनी पसंद की फिल्म दिखाने का अधिकार तो रखेगा ही."

हिमालय की बरबादी पर फिल्म बनाने वाले तेजबीर सिंह कहते हैं, "हमारे पास सिर्फ एक साल का समय है. अगले चुनावों को ध्यान में रखकर सरकारी मीडिया को कुछ विश्वसनीयता दिलाने की कोशिश हो रही है. कभी-कभी दूरदर्शनवालों का भी विवेक जाग उठता है." लेकिन तपन बोस कहते हैं, "मुझे तो यह सोचकर डर लगता है कि कहीं दूरदर्शन को ध्यान में रखकर ही न वृत्तचित्र बनने लगें."

■ लेकिन रमेश शर्मा जैसे भी निर्माता हैं जो दूरदर्शन के लिए फिल्में बनाते हैं मगर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण बनाए रखते हैं. पिछले साल दूरदर्शन के लिए बनाई 30 फिल्मों में उनका पहला वृत्तचित्र धारावाहिक 'कसौटी' भी है. वे अपने मन की बात कहने और प्रायोजकों की पसंद का ख्याल रखने की जद्दोजहद बखूबी निभाते हैं. वे कहते हैं, "दूरदर्शन की जरूरतें इतनी व्यापक हैं कि वाकई इससे आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिल सकती है." उनके सहयोगी राजीव मेहरोत्रा बताते हैं, "वे इस व्यवस्था के साथ काम करके भी व्यवस्था-विरोधी हैं. वे इस व्यवस्था के आलोचक हैं. और उन्हें कामयाबी भी मिल रही है."

■ मेहरोत्रा खुद भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित एक स्वतंत्र वृत्तचित्र निर्माता हैं. उनकी फिल्म 'द बैरेन हार्वेस्ट' को अप्रैल में फिल्म महोत्सव के जूरी के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया. फिल्म मानव शरीर में आयोडीन की कमी के बारे में है. इसके कारण शरीर और दिमाग दोनों कमजोर हो जाते हैं. उनकी फिल्म बहुत महान नहीं है लेकिन जैसा कि एक निर्देशक बताते हैं, "तमाम असुविधाओं के बावजूद यदि कोई निर्माता वृत्तचित्र बना लेता है तो वही बहुत बड़ी बात है."

मेहरोत्रा का विश्वास सभी दोषों के लिए सरकार पर आरोप मढ़ने के बजाय अपना मामला दुरुस्त रखने में ही है. वे कहते हैं, "हमें सकारात्मक फिल्म बनाने की जरूरत है. हम लोगों ने सिर्फ विरोध का रुख ही अपना रखा है. दूरदर्शन की नई पहल बेमिसाल है." वे इस विद्या में माहिर भी हैं.

■ और एक मणि कौल भी हैं, जो ऐसी फीचर फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं जिन्हें बहुत थोड़े ही लोग देखना पसंद करते हैं. उनका सबसे ताजा वृत्तचित्र कश्मीर पर है. कश्मीर पर बने वृत्तचित्र के लिए पैसा तो राज्य के पर्यटन विभाग ने दिया था पर यह वृत्तचित्र प्रचलित दायरे से हटकर बनाया गया है. कौल ने प्रकृति को जिस तरह चित्रित किया है उससे फिल्म किसी भी पहाड़ी प्रदेश की लग सकती है.

भारी-भरकम बजट के कारण कौल गरम हवा भरे बैलूनों और हेलीकॉप्टरों पर से दृश्यों को फिल्माने की छूट ले पाए हैं. पूरी फिल्म में कोई संवाद नहीं है. सेलोफोन पर एक अमेरिकी युवती का ध्रुपद शैली में बजाया रागश्री गूंजता रहता है. वे कहते हैं, "मैं सेजां (फ्रांसीसी चित्रकार) की तरह बनना पसंद करूंगा. वे चित्र तो सेब का बनाते थे पर इसी प्रक्रिया में वे कला में क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला रहे थे."

■ लेकिन ज्यादातर निर्माता कौल जितने खुशकिस्मत नहीं. पैसे की कमी उन्हें बनी रहती है. आमतौर पर देश के सभी वृत्तचित्र निर्माता दो अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं. पैसे के लिए वे विज्ञापन फिल्में बनाते हैं और दूसरे, अपनी प्रतिबद्धताओं और आस्थाओं के अनुकूल फिल्म बनाते हैं. रमेश शर्मा कहते हैं, "विडंबना यह है कि पहले तो आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फिल्म बनाते हैं. फिर दूसरी फिल्म में उन्हीं की खिंचाई करते हैं." पटवर्धन कहते हैं, "मुझे खुशी है कि इन फिल्मों से काफी पैसा नहीं बन पाता. अन्यथा लोग गलत फिल्मों का निर्माण करते."

नए युग की शुरुआत के संकेत तो मिल रहे हैं लेकिन यह भी याद रखना है कि यह तो शुरुआत भर है. अच्छे वृत्तचित्र क्या कुछ कर सकते हैं इसका हल्का एहसास भर ही हुआ है. जैसा कि पटवर्धन बताते हैं, "असली मुश्किल तो इन फिल्मों के लिए दर्शक जुटाने की है. दर्शक मिलने के बाद तो इसके अलावा कोई समस्या ही नहीं है."

—सिमरन भार्गव, नई दिल्ली और बंबई में.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रजनीकांत

दक्षिण का दमकता सितारा

अब अंग्रेजी फिल्म के जरिये अंतरराष्ट्रीय मंच पर आने की कोशिश में

कद से छोटे, रंग से काले, बिलकुल सामान्य शक्ल-सूरत के होने के बावजूद आज वे दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपर स्टार हैं. उनका नाम ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी है. यह नाम है रजनीकांत.

यह नाम पिछले करीब आठ वर्षों से दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में धूम मचाए हुए है. 115 फिल्मों से यह नाम जुड़ चुका है और प्राय: सबकी सब हिट. तभी तो आज वे इस हैसियत में पहुंच गए हैं कि अपने मन लायक भूमिकाएं चुन सकते हैं. इससे भी बड़ी बात यह कि अब वे साल में चार तमिल फिल्मों में ही काम करते हैं, शेष समय बंबइया हिंदी फिल्मों में. दक्षिण के दूसरे सभी अभिनेताओं में रजनीकांत ही एकमात्र ऐसे हैं जो बंबई की प्रतिद्वंद्विता में भी टिके हुए हैं. और अब तो वे अंग्रेजी फिल्मों की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं. एक्शन से भरपूर उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म 'ब्लडस्टोन' अगले महीने अमेरिका के 1500 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी.

यह उनके शानदार कैरियर का नया अध्याय साबित हो सकता है. रजनीकांत अब अंतरराष्ट्रीय फिल्म क्षितिज पर चमकने के महत्वाकांक्षी अभियान में लगे हुए हैं. पिछले पखवाड़े उन्होंने 'इंडिया टुडे' से कहा, "तमिल फिल्मों में मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां से आगे और कोई मुकाम नहीं. हिंदी फिल्मों के माध्यम से मेरी राष्ट्रीय छवि बनी है. अब मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं दुनिया भर में अपनी पहचान बनाऊं."

लेकिन उनके सबसे पक्के प्रशंसकों का भी मानना है कि रजनीकांत की असली प्रतिभा तमिल फिल्मों में ही सामने आ पाती है. वे एकमात्र ऐसे तमिल अभिनेता हैं जिनकी फिल्में शूटिंग शुरू होने के पहले ही बिक जाती हैं. कहा जाता है कि उन्हें हर फिल्म के लिए 25 लाख रुपए दिए

रजनीकांत 'कोडी परक्कुधु' में और (बाएं) 'ब्लडस्टोन' में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाते हैं. किसी भी दक्षिण भारतीय अभिनेता को अभी तक इतने पैसे नहीं मिले. पिछले साल दीवाली के मौके पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मनिथन' (मनुष्य) जबरदस्त सफल रही और नवीनतम फिल्म 'गुरु शिष्य' रिलीज होने के 50 दिन बाद भी हाउसफुल जा रही है. साउथ इंडियन फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध निर्माता और वितरक जी. वेंकटेश्वरन कहते हैं, "उनकी फिल्में राज्य के सबसे दूरदराज इलाकों में भी पहुंचती हैं जहां सिर्फ एमजीआर की फिल्में ही पहुंच पाती थीं."

रजनीकांत की एक तमिल फिल्म बनाने पर आमतौर पर 70 लाख रुपए का खर्च आता है. और यह फिल्म हाथोहाथ एक करोड़ रुपए से ऊपर में बिक जाती है. उनकी जो फिल्में सुपर हिट होती हैं वे दो करोड़ रुपए तक का कारोबार करती हैं. कुछ निर्माता उनकी पुरानी फिल्मों को भी खरीद रहे हैं और उनकी हिंदी फिल्मों को तमिल में डब करवा रहे हैं.

एक मामूली बस कंडक्टर से सुपर स्टार बन जाने का रहस्य क्या है. एक शब्द में कहें तो यह छवि का करिश्मा ही है. चौथी बार 'गुरु शिष्य' फिल्म देख चुकने वाला ऑटो ड्राइवर मणि कहता है, "रजनी मेरा हीरो है. उसकी फिल्में भले ही एक जैसी लगें लेकिन उसका स्टाइल गजब का है." चार वर्षीया श्वेता उन्हें रोज-रोज वीडियो पर देखकर भी नहीं थकती. तमिलनाडु में श्वेता की तरह के लाखों बच्चे 'रजनी स्टाइल' की नकल करते हैं और उन्हें सुपरमैन समझते हैं.

उनके सामान्य से पिछले जीवन और विवादास्पद फिल्मी कैरियर के कारण लोग उन्हें स्टार से ज्यादा व्यक्ति के रूप में चाहते हैं. उनके उग्र और लापरवाह स्वभाव के कारण शुरुआती दिनों में उनके बारे में तरह-तरह की अफवाहों का बाजार हरदम गरम ही रहता था. उनकी शराबखोरी और गुस्से की कहानियां लगातार सुनी जातीं. यह किस्सा भी काफी चर्चित हुआ कि कैसे उन्होंने एक बार मद्रास के एक पांच सितारा होटल के रेस्तरां में तोड़फोड़ की थी. फिर वे मानसिक संतुलन खो बैठे और उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा. इसके बाद उन्होंने कम फिल्में लेनी शुरू की और कॉलेज की एक छात्रा लता से शादी कर ली. अपने उस दौर को याद करते हुए रजनीकांत कहते हैं, "कुछ ही वर्ष पहले मुझे कंडक्टरी में 320 रुपए महीना वेतन मिलता था और एकाएक मुझे एक फिल्म के लिए पांच लाख रुपए मिलने लगे थे. प्रसिद्धि, पैसा और काम के दबाव के कारण मैं टूटने के कगार पर पहुंच गया था."

इसके बाद उनका आध्यात्मिक दौर शुरू हुआ और वे राघवेंद्र स्वामी (माधवा परंपरा के संत) के शिष्य बन गए. अपनी 100वीं फिल्म 'राघवेंद्र' में वे अपने गुरु की भूमिका में उतरे और उन्होंने एक नए धार्मिक संप्रदाय की लहर ही चला दी. वे हरे कृष्ण आंदोलन (इस्कॉन) के प्रशंसक भी हो गए और संन्यास लेने की बात करने लगे. फिल्मी पत्रिकाओं के अनुसार इसी अध्यात्मवाद के चक्कर में उनकी शादी भी टूटने के कगार पर पहुंच गई थी.

मजेदार बात यह है कि रजनीकांत मूलतः तमिल नहीं मराठी हैं. उनका असली नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है. बचपन बंगलूर के उपनगर बासवनगुडी में बीता. जब वे आठ वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था. उनके पिता और भाई ने उन पर ध्यान नहीं दिया. किसी तरह प्री-यूनिवर्सिटी तक उन्होंने पढ़ाई की. तंगी के कारण रजनीकांत ने हर तरह के काम किए. कुछ समय तक वे कुली भी रहे. आखिर में उन्हें कर्नाटक राज्य परिवहन निगम में बस कंडक्टर की नौकरी मिली. फिर जब एक्टिंग का भूत सवार हुआ तो वे मद्रास पहुंचे और साउथ इंडिया फिल्म

'भूखा शेर' में (नीचे); और 'मनिथन' में: लोकप्रिय लटके-झटके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चैंबर द्वारा चलाए जा रहे अभिनय कोर्स में दाखिला ले लिया. यहां प्रसिद्ध निर्देशक के. बालाचंदर की नजर उन पर पड़ी.

और शिवाजीराव बन गए रजनीकांत. बालाचंदर ने अपनी फिल्म 'अपूर्व रागेगल' (अजूबे राग) में उन्हें खलनायक की भूमिका दी. उनकी अगली फिल्म थी 'मुंडु मुडिचु' (तीन गांठें). इसमें भी वे खलनायक थे, पर यह रोल अधिक अच्छा था. बालाचंदर बताते हैं, "रजनी मुझे पहला ऐसा अभिनेता मिला जो खलनायक की भूमिका करने पर जोर देता रहा." लेकिन भारती राजा के '16 वयाधिनिले' (16 वर्ष की उम्र) ने तमिल फिल्मों की दिशा बदल दी. इस फिल्म के हीरो थे कमलहासन, हीरोइन थीं श्रीदेवी और खलनायक थे रजनीकांत. और तीनों रातोरात सितारे बन गए. 'रजनी स्टाइल' ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया. लेकिन इसके साथ ही उन्हें विलेन की जगह हीरो का रोल मिलने लगा और 'धरमयुद्ध' से उन्होंने इसकी सफल शुरुआत भी की.

उनकी अगली बेहद सफल फिल्म थी ए.के. बालाजी की 'बिल्ला' जो अमिताभ बच्चन की फिल्म 'डॉन' का तमिल रूपांतरण थी. इसी फिल्म से रजनीकांत कमलहासन से भी आगे निकलकर दक्षिण के नंबर एक हीरो बन गए. भारती राजा कहते हैं, "कमलहासन महान कलाकार हैं लेकिन जनता का हीरो तो सिर्फ रजनीकांत ही है." के. बालाचंदर ने कहा, "तमिल फिल्मों में रजनीकांत की तरह की कोई शख्सियत अब तक नहीं आई थी. एक आम आदमी भी अपने आप को इस स्टार से जुड़ा हुआ मानता है. इसकी वजह यह है कि वह उसी की तरह का दिखता है."

लेकिन विडंबना यह है कि लाखों का चहेता यह स्टार एकदम अकेला है. नरम मिजाज रजनीकांत प्रेस के लोगों से शायद ही कभी मिलते हैं. वे मानते हैं कि ये लोग उन्हें पसंद नहीं हैं. उनका कोई करीबी दोस्त नहीं है और सेट पर भी वे अपने आप में ही सिमटे रहते हैं. शूटिंग के अलावा वे मद्रास के कुलीनों की बस्ती पोएस गार्डन के अपने तीन कमरे वाले साधारण से घर से शायद ही कभी बाहर निकलते हैं. रजनीकांत कहते हैं, "मैं एक साधारण आदमी हूं और मेरी पसंद भी साधारण है. मैं नहीं मानता कि स्टार होने का अर्थ यह है कि आपके पास सारी विदेशी चीजें ही हों." वे अपनी 1980 मॉडेल की प्रीमियर पद्मिनी कार खुद ही चलाकर शूटिंग वगैरह की जगहों पर जाते हैं.

उनकी पत्नी लता कहती हैं, "आज वे एकदम बदले हुए आदमी हैं, सत्य की तलाश में लगे एक आध्यात्मिक आदमी जैसे." लता को लगता है कि पत्र-पत्रिकाओं ने उन दोनों के मतभेदों के किस्से को बढ़ा-चढ़ाकर छापा है. रजनीकांत की दो बेटियां हैं. छह वर्षीया ऐश्वर्य और तीन वर्षीया सौंदर्य. रजनीकांत अपने को आध्यात्मिक शांति की तलाश में लगा व्यक्ति मानते हैं और दर्शन की ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं. उन्होंने बड़ी होशियारी से अपनी अधिकांश कमाई जायदाद खरीदने में लगा दी है. आजकल वे मद्रास में एक करोड़ रुपए की लागत से कल्याण मंडपम (विवाह भवन) बनवा रहे हैं.

उनके साथ काम करने वालों के दिल में उनके लिए सिर्फ प्रशंसा ही है. तमिल फिल्मों की अभिनेत्री राधा कहती हैं, "वे सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर भीड़ खींचने वाले स्टार ही नहीं, बहुत अच्छे आदमी भी हैं." सहयोगी अभिनेता श्रवणन कहते हैं, "सेट पर वे बहुत अनुशासित रहते हैं. इतने अनुशासन की बात तो निर्माता सिर्फ सपने में ही सोच सकता है."

लोगों के मन में जो जगह उन्होंने बनाई है, उससे यह तय है कि सभी राजनैतिक पार्टियां उनके पीछे लगें. लेकिन वे कहते हैं, "मैं मौजूदा राजनैतिक माहौल से नफरत करता हूं. किसी भी राजनैतिक पार्टी के साथ मेरा नाम कभी नहीं जुड़ेगा."

सुपर स्टार बन गए रजनीकांत के प्रशंसक क्लबों की संख्या आज करीब 8,000 है जो सिर्फ तमिलनाडु में ही हैं. अब वे अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल करना चाहते हैं. 'ब्लडस्टोन' के बाद अभी हाल में उन्होंने मणि रत्नम ('नायकन' वाले) की एक्शन फिल्म की शूटिंग आस्ट्रेलिया में पूरी की है. उनका मानना है कि शिखर पर होते हुए फिल्मों से संन्यास लेना सर्वोत्तम होगा. वे कहते हैं, "1990 तक मैं संन्यास ले लेना चाहता हूं. स्टार होने का मजा अब कम होता जा रहा है." लेकिन रजनीकांत अगर रजनीकांत हैं तो बस अपने मूड और अपनी रहस्यमयता के कारण. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सैकड़ों निर्माताओं का सब कुछ उनके कारण ही दांव पर लगा हो तो क्या वे अपने मन की कर पाएंगे? बहरहाल, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा.

—श्रीधर पिल्लै, मद्रास में

पत्नी लता के साथ; और (नीचे) पूजा घर में: आध्यात्मिक शांति की खोज

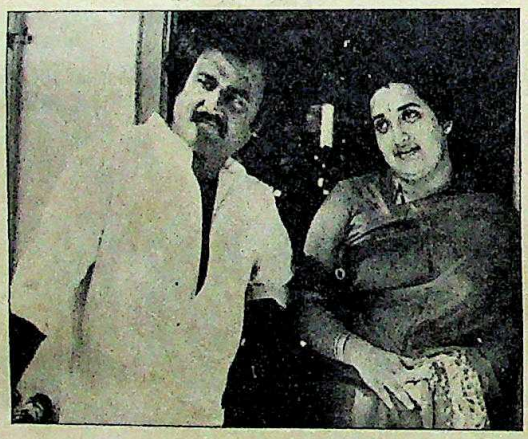

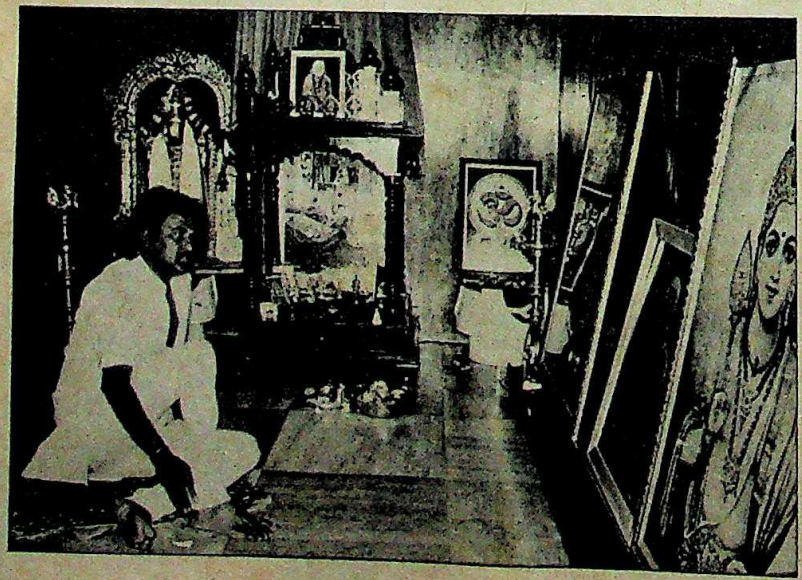

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाल नाटक

नन्हे कलाकारों के सपने

बाल नाट्य समारोह से हिंदी बाल रंगमंच की नई आशाएं

दिल्ली में जहां रंगमंच का दायरा कुछ गिने-चुने बुद्धिजीवियों और 'संभ्रात' लोगों के एक सीमित वर्ग तक बंध कर रह गया है, पिछला पखवाड़ा एक अनूठा परिवर्तन लेकर आया. नाटक प्रदर्शनों के दौरान 'बच्चों के लिए निषिद्ध' कमानी ऑडिटोरियम पर लगातार तीन दिन तक बच्चों का एकछत्र राज रहा.

26, 27 और 28 जून के दिन दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में रहने वाले लगभग 250 बच्चों ने स्वयं तैयार किए छह नाटक पेश किए. इधर मंच पर बच्चों का एकाधिकार था तो उधर हॉल में भी नाटक देखने आए बच्चों की संख्या अभिभावकों और दूसरे वयस्कों के मुकाबले कहीं अधिक थी. दिल्ली रंगमंच के इतिहास में ऐसे अवसर विरले ही रहे होंगे जब हॉल अपनी क्षमता से ऊपर खचाखच भर गया हो और बच्चों की किलकारियों से लगातार गूंज रहा हो. दर्शकों में अधिकांश बच्चे और उनके माता-पिता ऐसे थे जो अपने जीवन में पहली बार किसी व्यावसायिक स्तर के हॉल में बैठकर नाटक देखने का आनंद ले रहे थे.

बाल नाटकों का यह मेला दिल्ली के छह इलाकों में दिल्ली प्रशासन की साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित रंगमंच कार्यशालाओं की देन था जिनमें 8 से 13 साल की उम्र वाले स्थानीय बच्चों ने हिस्सा लिया और इनका संचालन दिल्ली के अनुभवी रंगकर्मियों ने किया. ऐसी कार्यशालाओं की शुरुआत 1978 में ब.व. कारंत और सुषमा सेठ जैसे रंगकर्मियों ने की थी.

हालांकि अभिनय, निर्देशन, कहानी और मंचसज्जा की दृष्टि से लगभग हर नाटक में कुछ न कुछ कमियां थीं पर दिल्ली रंगमंच के जाने-माने रंगकर्मी रमेश मनचंदा के अनुसार, "कार्यशालाओं का असली उद्देश्य एक ही बार में बच्चों को अभिनेता बना देना या व्यावसायिक नाटक तैयार करना नहीं बल्कि उनमें यह जागृति पैदा करना है कि हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है."

विजयदान देथा की कहानी पर आधारित नाटक 'समय अनमोल' (निर्देशन: अमित उद्गाता) को छोड़ शेष सभी नाटकों की पटकथा बाल-कलाकारों और सहयोगी रंगकर्मियों ने तैयार की. चितरंजन पार्क कार्यशाला के बच्चों द्वारा लिखित और अभिनीत 'खेल खेल में' (निर्देशन: आशिष घोष) एक स्वार्थी लड़की की कहानी है जो परी से मिले वरदान के बावजूद अपने ही जाल में फंस जाती है; 'छोटे-छोटे सपने' (निर्देशन: रमेश मनचंदा) उन कामकाजी बच्चों की कहानी है जिन्हें गरीबी की वजह से अपने सपनों को कुचल कर पढ़ाई के बजाय मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है.

फोटो: अनूप अस्थाना

'हताओ! आबा! आबा!' के एक दृश्य में आदिवासी लोग: शानदार प्रस्तुति

नाटक महोत्सव की सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति अखिलेश खन्ना के निर्देशन में प्रेसीडेंट एस्टेट कार्यशाला के बच्चों द्वारा तैयार किया गया नाटक 'हताओ! आबा! आबा!' रही जिसमें धर्म की आड़ में काम करने वाले अपराधियों द्वारा भोले-भाले आदिवासियों के शोषण का चित्रण किया गया है. इस नाटक की मंचसज्जा, कलाकारों का अभिनय और प्रकाश व्यवस्था इतनी प्रभावशाली और व्यावसायिक दर्जे की रही कि कमानी और श्रीराम सेंटर में प्रस्तुत किए जाने वाले कई व्यावसायिक नाटक भी इसके सामने फीके दिखाई देंगे. नाटक समारोह की इस सफलता से निकट भविष्य में सुनियोजित बाल रंगमंच की कल्पना की जा सकती है.

रंगमंच कार्यशाला के पीछे काम करने वाले फलसफे के बारे में परिषद के सचिव सुरेंद्र माथुर कहते हैं, "इनके माध्यम से समाज के प्रति बच्चों के नजरिये और इस तरह उनके व्यक्तित्व विकास को भी रचनात्मक दिशा दी जा सकती है." एअर फोर्स सेकेंडरी स्कूल (पालम) में आठवीं कक्षा की छात्रा और 'छोटे-छोटे सपने' में अभिनय करने वाली 12 वर्षीया इंद्रप्रीत बताती हैं, "मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हमारे घर में सफाई करने वाली लड़की और दुकानों पर काम करने वाले बच्चों की भी हम जैसी भावनाएं होती हैं. अब उनके प्रति मेरा नजरिया बदल गया है."

इस तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी रंगमंच को होने वाले फायदे के बारे में मनचंदा का कहना है, "अगर इन में से पांच अच्छे कलाकार भी तैयार हो गए तो यह एक अच्छी उपलब्धि होगी नहीं तो कम से कम इन बच्चों और हजार से अधिक उनके परिवार वालों में रंगमंच के प्रति लगाव तो पैदा होगा ही." दर्शकों के अकाल से पीड़ित रंगमंच के लिए फिलहाल इतनी उपलब्धि भी काफी है.

—विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संस्मरण

संघर्ष पीड़ा और सत्ता सुख

वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता की लंबी राजनैतिक यात्रा का वृत्तांत

पंडित कमलापति त्रिपाठी की पुस्तक 'स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद' को न इतिहास कहा जा सकता है, न आत्मकथा. यह उनकी लंबी जीवन-यात्रा के संस्मरणों का संकलन भर लगता है जिसमें कहीं इतिहास झांकता है तो कहीं आत्मकथा किल्लोल करती है. कुल मिलाकर यह गांधी के त्याग युग का उपसंहार और 1947 के बाद के भोग युग की त्रासदी का परिपाक लगता है.

इतिहास लेखन की कुछ मूलभूत शर्तें होती हैं जिनमें घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, तिथियों के बारे में और नामों व घटनाओं के बारे में विश्वस्त जानकारी अपेक्षित होती है. इस लिहाज से प्रस्तुत पुस्तक कतई कसौटी पर खरी नहीं उतरती क्योंकि पंडित जी ने न तो घटनाओं की तिथियों के बारे में पक्के तौर पर कुछ लिखा है, न ही उनका क्रमवार विवरण है. बल्कि अक्सर इन मुहावरों का सहारा लिया गया है—'सुना जाता है कि', 'सुनते हैं कि', 'कहते हैं कि' आदि-आदि.

दूसरी ओर आत्मकथा लेखन का तकाजा यह है कि लेखक अगर अपने सकारात्मक पहलुओं का बखान करता है तो उसमें अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं की आत्मस्वीकृति और आत्मविश्लेषण का भी साहस परिलक्षित होना चाहिए. प्रस्तुत पुस्तक में यह तत्व लगभग गायब है.

कमलापति जी की जीवन-यात्रा गांधी युग के त्याग-तकलीफ और संघर्ष से शुरू होकर भोग-विलास के गलियारे में पड़ाव डालती है. संघर्ष की पीड़ा और सत्ता सुख का भोग दोनों के खट्टे-मीठे स्वाद चखे हैं पंडित जी ने. जो जिया-भोगा उन्हें 48 लेखों के सांचे में ढाला है. अपनी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि "शायद मेरी इन बातों से आने वाली पीढ़ियां उस महान ऐतिहासिक युग की एक हल्की-सी झलक पा सकें जो युग मेरी आंखों के सामने यात्रा कर रहा था." और सचमुच यह उस युग की बहुत हल्की झलक ही देता है क्योंकि उन्होंने कई ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाक्रमों को अछूता छोड़ दिया (शायद बरबस छूट गया हो क्योंकि उन्होंने लिखने के लिए अत्यंत व्यापक कालखंड चुन लिया). कई जगह साफ लगता है कि उसे उकेरने में, उद्घाटित करने में वे बुरी तरह उलझ गए हैं.

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद का व्यापक कालखंड चुना शायद इसी वजह से उसके प्रति न्याय करने में सफल नहीं रहे. स्वतंत्रता आंदोलन की ही बात करें तो कहना होगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की अनदेखी करने की कोई गलती नहीं कर सकता. कमलापति जी ने यह जिक्र तो किया है कि वे भी कांग्रेस समाजवादी दल

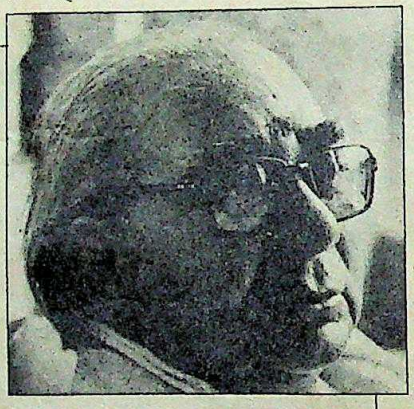

"मैं किसी व्यक्ति का अंध भक्त नहीं, न किसी परिवार का 'लॉयल' हूं. मैं पंडित जी का साथी रहा इसलिए कि उनमें कांग्रेस की संस्कृति और आदर्शों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा...इंदिरा गांधी में भी मैंने कांग्रेस की संस्कृति की प्रतिछाया देखी"

के सदस्य रहे लेकिन 42 के आंदोलन में लोहिया, जयप्रकाश सरीखे नेताओं की भूमिका की वे साफ अनदेखी कर गए हैं.

फिर, आजादी के साथ ही बंटवारे की जिस त्रासदी से इस भूखंड को गुजरना पड़ा वह शायद उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई वरना उसका उल्लेख जरूर होता उनकी पुस्तक में. आजादी के बाद के दौर का उल्लेख करें तो गोवा मुक्ति संघर्ष, भारत-चीन सीमा विवाद और उसके बाद कांग्रेस के उत्तरोत्तर बिखराव, राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के गठन वगैरह का हल्का-सा उल्लेख भी नहीं किया गया है. इमरजेंसी लगाना और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करना भूल थी यह तो उन्होंने कबूल किया लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करना भूल गए जो इमरजेंसी लगाने में निर्णायक रहा. जनता पार्टी की 'असाधारण सफलता' का जिक्र तो उन्होंने किया मगर सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी को मिली पराजय किसके हाथों हुई यह बताना शायद उन्होंने उचित नहीं समझा. ऐसी कई छोटी-बड़ी भूलें हैं जो सचमुच खलती हैं.

कांग्रेस पार्टी की आज की कमजोरियों को बेशक लेखक ने समझा और परखा है. कहीं-कहीं उनकी अंतर्व्यथा फूट पड़ती है. "आज की कांग्रेस की कमजोरी का कारण यह है कि धरती के वास्तविक कार्यकर्ता उपेक्षित हैं. उनका स्थान चाटुकारों ने ले रखा है. यह चाटुकार वर्ग नेताओं की परिक्रमा करता रहता है, और उसी से कृपा पाने की आशा कर लेता है और जनता से पार्टी का संबंध टूट जाता है. यही कारण है कि राजनैतिक दल निर्बल और निर्जीव हो जाते हैं." वे लिखते हैं, "जनता यह समझती है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है. बड़े-बड़े प्रस्ताव पास किए जाते रहे हैं. चुनाव में कांग्रेसियों को जिताने की कांग्रेसी सरकारें बनाई जाती हैं पर कांग्रेस के निर्णय कार्यान्वित नहीं हो पाते."

बीते जमाने की याद करते हुए कमलापति जी एक जगह लिखते हैं, "कांग्रेस के में प्रमुख रूप से यह बात रही है कि मतभेद होने पर भी पारस्परिक सद्भाव और सौजन्य बना रहे." आगे चलकर पंडित जी को अफसोस दल में इसका अभाव बुरी तरह खटकता है और वे मौजूदा परिस्थिति की आलोचना करते हैं.

एक जगह अपनी सफाई देते हैं, "मैं किसी व्यक्ति का अंध भक्त नहीं, न किसी परिवार का 'लॉयल' हूं. मैं पंडित जी का साथी रहा और जीवन पर्यंत उनका साथ दिया इसलिए कि मुझे जवाहर लाल जी में कांग्रेस की संस्कृति और उसके सिद्धांतों और आदर्शों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा." लेकिन इसी पुस्तक में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि बार-बार चाहकर भी इंदिरा जी के किसी अनुचित (आदेश) को ठुकराने में असमर्थ रहे. एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, "इंदिरा जी पर प्रादेशिक नेताओं के प्रभाव को कम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और उन लोगों को काट-छांट कर उन्हें ऐसा बना दिया कि वे प्रभावहीन होकर संगठन और सरकार को वह सहयोग और बल प्रदान करने में अक्षम हो गए जिनसे यह आशा की जा सकती थी." उन्होंने उन परिस्थितियों का विवरण दिया है जिनमें उन्हें 1980 में रेलमंत्री पद और 1986 में कांग्रेस (इ) के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना पड़ा.

जाहिर है उक्त तीखी टिप्पणियों के चलते कांग्रेसी हलके में खलबली मचती, और ऐसा हुआ भी. दबी-छिपी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गईं लेकिन किसी ने अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसा करने से शायद पंडित जी के आरोपों की ही पुष्टि होती.

पंडित जी स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक होने के साथ-साथ एक चोटी के पत्रकार भी रहे हैं. उनका पत्रकार इस पुस्तक पर शुरू से अंत तक हावी है. जैसा कि कहा जाता है, पत्रकारिता त्वरा का साहित्य है. इस कसौटी पर उनकी यह पुस्तक खरी उतरती है. इसमें कहीं-कहीं भावातिरेक भी है और मर्मस्पर्शी प्रसंग भी. पंडित जी ने पिछले 54 वर्षों से फलों का राजा आम का स्वाद नहीं चखा. कथा काफी मर्मस्पर्शी है. पंडित जी के ही शब्दों में, "मेरी पत्नी के मरने के दो घंटे पूर्व बनारस के महाराजा के यहां से आम के फल के टोकरे उन्होंने देखे. लंगड़ा आम की टोकरी उन्होंने देखी और खाने की इच्छा प्रकट की. मैं कदाचित उन्हें आम खिला देता परंतु जो डॉक्टर उस समय दवा दे रहे थे, उन्होंने आम खिलाने से मना कर दिया... मुझे दुख हुआ कि आम मैं उन्हें नहीं खिला पाया. तब से आज तक करीब 54 वर्ष बीत गए, मैंने आम नहीं खाया. मुझे प्रसन्नता है कि आम न खाने का मेरा दृढ़ निश्चय रहा."

उन्हें इस बात का खेद है कि उनकी मुद्रा को देखकर और उनके माथे पर भस्म और चंदन तथा रोली के टीके को देखकर यह धारणा पैदा होती है कि वे कोई कट्टरवादी हिंदू हैं जो छुआछूत और जात-बिरादरी को मानते हैं. 'परिवार से विद्रोह' शीर्षक लेख में लिखते हैं, "बहुत से लोग मुझे एक कट्टर सांप्रदायवादी मानते हैं. मैं उनकी धारणाओं को अपने ही दोष के कारण दूर नहीं कर पाया." इस पुस्तक में उन्होंने यह जताने की बार-बार चेष्टा की है कि न वे जात-पांत मानते हैं और न ही उनका छुआछूत में विश्वास है. पुनरावृति का दोष उन पर इस कर्म में बनता है. तिलक-दहेज न लेने का कर्म भी किया है उन्होंने.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रभाव की चर्चा पुस्तक में कई जगह है और वे अब भी गांधी के रास्ते पर चलकर राष्ट्रीय मसलों को हल करना संभव मानते हैं. गांधी जी को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखते हैं, "गांधी का युग क्रांति का युग था और उस युग ने केवल राजनैतिक क्रांति नहीं की बल्कि उसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी हुई. एक प्रकार से गांधी ने भारत के मानव को नया मानव बना दिया. यद्यपि उस युग की मान्यताएं आज विलुप्त हो रही हैं जिसके फलस्वरूप हमारा सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन भी नीचे गिरा है. आज दुख की बात है कि इसी कारण राष्ट्र संकट में दिखाई दे रहा है."

लेखक इस बात से दुखी है कि निर्भयता, जो गांधी जी ने देश को प्रदान की थी उसका

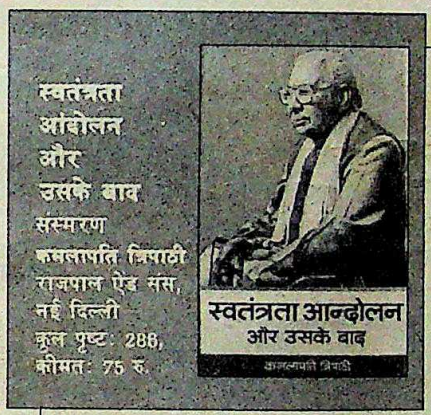

"आज की कांग्रेस की कमजोरी का कारण यह है कि धरती के वास्तविक कार्यकर्ता उपेक्षित हैं. उनका स्थान चाटुकारों ने ले रखा है...जनता से पार्टी का संबंध टूट जाता है...जनता यह समझती है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है"

स्थान भय और असत्य ने ले लिया. असत्य संभाषण और स्वार्थलोलुपता का बाजार गरम हो गया है. परस्पर अविश्वास फैला है. कथनी और करनी में इतना अंतर है कि मालूम नहीं होता कि भविष्य में क्या बनने वाला है.

लेकिन इससे भी अधिक दुखदायी तो यह है कि स्वयं कमलापति जी गांधी जी के आदर्शों को छिन्न-भिन्न होते निरुपाय टुकुर-टुकुर ताकते रहे. गांधी जी की करुणा ने तो उन्हें आजीवन विगलित किया लेकिन अन्याय के विरुद्ध गांधी जी के 'आक्रोश' वाले पक्ष को वे आत्मसात नहीं कर पाए. गांधी जी के इस पक्ष को उनके निधन के बाद जिंदा रखने की कोशिश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत हद तक की. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तो उन्होंने जेलयात्रा की ही उसके बाद भी गरीबों, शोषितों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ते हुए जेल की यातनाएं भुगतीं. तब कमलापति जी सत्ता के गलियारे में विराजमान थे.

लेकिन खैरियत यह है कि पंडित जी ने बाद में अपनी ही पार्टी की कमजोर नसों पर उंगलियां रखनी शुरू की. लेकिन तबतक बहुत देर भी हो चुकी थी. उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोकतंत्र पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. तभी तो उन्होंने एक जगह लिखा है, "आज तो लोकतंत्र के रहते मतभेदों के लिए कोई स्थान नहीं है और स्थिति तो तब और गंभीर हो जाती है जब शासन-सत्ता अपने को सुरक्षित रखने के लिए मतभेद को, आवश्यक हो तो बलपूर्वक कुचल देने के लिए आगे बढ़ती है. ऐसा होता है तो लोकतंत्र की जड़ खोदी जाने लगती है और उसका स्थान निरंकुश शासन और फासिस्टवाद ग्रहण करने लगता है."

हिंदी प्रेमी कमलापति जी को इस बात का भारी क्षोभ है कि हिंदी की उपेक्षा हिंदी वालों की ओर से अधिक है, "जो लोग हिंदी में बोल सकते हैं वे भी अंग्रेजी में ही बोलना पसंद करते हैं... स्थिति यहां तक दयनीय है कि कोई विदेशी राजनयिक हमारे देश में आता है, वह अपने देश की भाषा में बोलता है परंतु उसके स्वागत आदि में हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में ही बोलते हैं."

कमलापति जी ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि इमरजेंसी लगाना भूल थी. वे मानते हैं कि उससे बड़ी भूल ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी करनी थी जो आदर की दृष्टि से देखे जाते थे. जेपी की गिरफ्तारी को लेकर वे काफी खिन्न थे.

लेकिन पुस्तक का अंत उन्होंने जिस चेतावनी के साथ किया है उसका सहभागी होना कठिन है वे कहते हैं कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है और यदि कांग्रेस टूटती है तो देश के टूटने का डर पैदा होता है. पंडित जी भूलते हैं कि खुद गांधी जी आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देने के हक में थे. वैसे भी किसी दल को देश का पर्याय नहीं माना जा सकता.

—गुरु कृपाल सिन्हा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर्यावरण

प्रपंच का पर्दाफाश

विकास संबंधी आधुनिक अवधारणाओं पर चिंता और तीखे सवाल

हमारा पर्यावरण
पर्यावरण
संपादन: अनुपम मिश्र
पर्यावरण कक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
कुल पृष्ठ: 280; कीमत:200 रु.

गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष ने दूसरी कई संस्थाओं के सहयोग से 'हमारा पर्यावरण' पुस्तक तैयार कर इस भरोसे को अधिक मजबूत किया है कि गांधीवादी भले ही आजादी पूर्व जैसा विराट जनांदोलन आज खड़ा न कर सकें किंतु समाज के संकटों और उसकी चिंताओं का उन्हें गहरा एहसास है. और वे लोग न तो चुप बैठे हैं, न निष्क्रिय ही हुए हैं.

कोई चार साल पहले 'देश का पर्यावरण' पुस्तक कई भाषाओं में प्रकाशित कर इस संस्था ने आजादी के बाद के वैज्ञानिक अभियान और प्रौद्योगिक प्रपंच को एक चिंतनीय सवाल के रूप में उठाया था. तब देश में पर्यावरण को लेकर इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी. किंतु भोपाल गैस त्रासदी के बाद तो प्रायः हर आदमी के दिमाग में अपने अस्तित्व की सुरक्षा और विकास संबंधी आधुनिक अवधारणाओं को लेकर एक गहरी चिंता व्याप्त हुई है. जितना भय आज तीसरे विश्वयुद्ध को लेकर है उससे कम रोज बिगड़ते पर्यावरण को लेकर नहीं है. इसका संकेत पुस्तक की भूमिका से भी मिलता है, "नए कायदे-कानून बने हैं, पर्यावरण संवारने के कुछ आंदोलन भी उभरे हैं, पर बिगड़ता पर्यावरण बिगड़ता ही जा रहा है, क्योंकि विकास की धारणाएं और उन धारणाओं को पालने-पोसने वाली जो जीवन शैली है वह अबाध गति से फैलती ही जा रही है. यह फैलाव समाज के एक छोटे-से हिस्से में ही हुआ है पर उसने समाज के बड़े हिस्से के सोचने-समझने की भाषा हर ली है और आगे आकर कुछ करने की शक्ति भी छीन ली है."

> **"नए कायदे-कानून बने हैं, पर्यावरण संवारने के कुछ आंदोलन भी उभरे हैं, पर बिगड़ता पर्यावरण बिगड़ता ही जा रहा है क्योंकि विकास की धारणाएं और उन धारणाओं को पालने वाली जीवन शैली अबाध गति से फैलती जा रही है"**
>
> 'हमारा पर्यावरण' की भूमिका से

प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक 'देश का पर्यावरण' में पर्यावरण संबंधी विविध विषयों की प्रारंभिक जानकारी थी तो इस पुस्तक में पर्यावरण के पीछे की राजनीति को नंगा करने की एक जबरदस्त मुहिम का असरकारी श्रीगणेश किया गया है. कैसे प्राकृतिक संपदा पूरे समाज के हाथों से छीन कर कुछ ही लोगों का जीवन चलाने के लिए तहस-नहस की जा रही है. किस तरह इस संपदा के भिन्न-भिन्न रूपों पर समाज के भिन्न-भिन्न अंग टिके थे और आज विकास के नाम पर कैसे ये जीवन आधार टूट चले हैं और इस कारण स्त्री-पुरुषों, गांवों-शहरों, पशु-पक्षियों पर क्या-क्या बीत रही है.

पूरी पुस्तक का शब्द-शब्द इसी गहरी चिंता का पर्याय बन गया है जिसमें भूमि, जल, वन, बांध, वातावरण, शहरी रहन-सहन, लोग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जीवन संपदा, राज-समाज, पर्यावरण और अंत में पर्यावरण की राजनीति पर तथ्यपूर्ण विचार-विमर्श तथा झकझोर देने वाली जानकारियों का ब्यौरा पेश किया गया है. इस रूप में यह पुस्तक समाज विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय पहल है. केवल संपादन कला की दृष्टि से ही नहीं, अपने योजनाबद्ध उद्देश्य की दृष्टि से भी यह हिंदी की संभवतः पहली पुस्तक है जिसमें इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ते देश को ठहर कर सोचने, समझने और संभव बन पड़े तो नए सिरे से विचार कर अगला कदम रखने का इशारा किया गया है. सारे देश के पापों को कथित रूप से धोने वाली गंगा के किनारे बसे 1500 उद्योगों ने अपना जहरीला पानी उसमें मिला दिया है. यमुना के किनारे लगे उद्योग साठ डिग्री से.ग्रे. गरम पानी यमुना में छोड़ते हैं जिससे मछलियों का जीना मुश्किल हो जाता है. उत्तर प्रदेश में काली नदी में चीनी की 24 मिलों की गंदगी गिराई जाती है. जब ये नदियां यही प्रदूषित पानी लेकर समुद्र में मिलती हैं तो वहां भी असर पड़ता है और सारा वातावरण संक्रामक बन जाता है. समाज क्या इस विभीषिका से अपनी रक्षा किसी तरह कर सकता है?

आजकल गांवों के कई बड़े किसान सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के प्रोत्साहन पर सफेदा जैसे पेड़ों की खेती कर रहे हैं. निश्चय ही इससे उनकी पौ बारह हो गई है. मगर यह पुस्तक चेतावनी देती है, "लेकिन गांव के बेजमीन लोगों के लिए यह कहर है. इससे इंधन भी नहीं मिलेगा और चारे की बात ही बेकार है. यों देखा जाए तो चारे की समस्या इंधन से भी बड़ी है. सफेदे के समर्थक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उद्योगों और शहरों की जरूरत एक बार पूरी हो जाए तो फिर लकड़ी का भाव गिरेगा और किसान फिर पेड़ों की किस्में बदल सकेंगे. लेकिन वे इस सवाल का जवाब नहीं देते कि किसान भला उन गरीबों के लिए लकड़ी क्यों पैदा करने लगेंगे जो दाम नहीं चुका सकते?" कुल मिलाकर हमारा यह विकास भारत की गरीब और मजदूर आबादी के ध्वंस की कीमत पर होगा.

इस ध्वंस और राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचने का ठेका सिर्फ चुनी हुई सरकार ही नहीं ले सकती, गैर-सरकारी जनसंगठन भी यह अधिकार रखते हैं, इसे यह पुस्तक बखूबी साबित करती है. इस संदर्भ में इस पुस्तक का यह उद्धरण बहुत उपयुक्त लगता है, "आजादी के बाद देश में राजनैतिक बहस बराबरी और विकास के दो ही मुद्दों के आसपास केंद्रित रही है. पर्यावरण संबंधी चिंता ने इस तीसरा आयाम जोड़ा है: संपोषण का. अ देश की सबसे बड़ी चुनौती समानता औ संपोषण लाने वाली विकास प्रक्रिया को पह चानने और लागू करने की है." इस चुनौती का एहसास यह पुस्तक बखूबी कराती है कथित बुद्धिजीवियों और सुशिक्षितों तक भी यह पुस्तक पहुंचती है तो यह उनका ही सौभाग्य होगा जो अपने को समाज प्रेमी कहते हैं.

—विजय बहादुर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डालमिया रिसॉर्ट्स में यूनिट ले कर, आप भी यही कह सकते हैं।

मिस्टी मीडोज़: पहलगाम

बर्फीली चोटियों वाले पहाड़ों की तलहटी में, और खूबसूरत लिडर नदी के सामने है डालमिया रिसॉर्टस की नवीनतम पेशकश मिस्टी मीडोज़। इस रिसॉर्ट के 75 रिहायशी यूनिट 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में चीड़ के पेड़ों के बीच फैले हुए हैं।

मिस्टी मीडोज़ अप्रैल 1989 तक रहने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर आपके आनंद के लिए आपके पास 2054 तक रहेगा।

लक्ज़री रिसॉर्ट की सुविधाएं—जीवन भर आपके साथ।

सेन्ट्रली हीटेड अपार्टमेंट्स
*रेस्टारेंट *कॉफी शाप *बार *ओपेन एयर बार-बे-क्यू *चिल्ड्रेंस पार्क *हेल्थ क्लब *डिपार्टमेंटल स्टोर *ब्यूटी सैलून *ट्रैवल ऐजेंसी *गोल्फ *ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग *ऐंगलिंग और इसके अलावा भी बहुत, बहुत कुछ।

वैकेशन लाइसेंसिंग—अनेक बड़े फायदे।

*वैकेशन लाइसेंसिंग में, आप रिसॉर्ट में एक यूनिट हर साल एक निश्चित सप्ताह या सप्ताहों के लिए उपयोग करने का अधिकार खरीद लेते हैं।

*आपके छुट्टियां मनाने पर बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा।

*आप अपने यूनिट सप्ताह/सप्ताहों को बेच सकते हैं। किराए पर या किसी को उपयोग के लिए दे सकते हैं। उपहार में दे सकते हैं। या वसीयत में दे सकते हैं — जिसे चाहें उसे।

लागत की बात

कीमतें सीज़न और यूनिट टाइप के अनुसार रु. 12,000 से ले कर रु. 30,500 तक हैं। साथ में मामूली रखरखाव डिपाज़िट। और यदि जरूरी हुआ तो वार्षिक रखरखाव के लिए थोड़ी फ़ीस।

भुगतान के लिए किश्त योजना भी है जिसमें अभी तक का तुरंत भुगतान रु. 3,800 से लेकर रु. 12,700 तक है।

रिसॉर्ट की कुछ सुविधाएं पैसा देकर होंगी और कुछ बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिलेंगी।

हर साल छुट्टियों के लिए एक नई जगह

मिस्टी मीडोज़ का सदस्य बनने पर आप भारत भर में फैले अन्य डालमिया रिसॉर्टों के वैकेशन ओनरों से अपने यूनिट सप्ताह बदल सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय वैकेशन एक्सचेंज कम्पनी के साथ सम्बद्ध होने के लिए बातचीत चल रही है। ऐसा हो जाने पर आप विदेशी रिसॉर्टों के साथ भी अपने वैकेशन सप्ताह बदल सकेंगे।

मिस्टी मीडोज, पहलगाम, आपकी दिलकश दिल पसंद जगह।

कृपया मिस्टी मीडोज़ रिसॉर्ट, पहलगाम का पूरा ब्योरा मेरे पास भेजिए। मैं समझता हूं कि यह ब्यौरा मुफ्त होगा और इससे मेरे ऊपर खरीदने का कोई बंधन नहीं होगा

नाम .....

पता .....

.....

.....

टेलीफोनः आफिस ..... घर .....

Misty Meadows
A DALMIA RESORT

यह कूपन काट कर इस पते पर भेजिएः—

डालमिया रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
पहली मंजिल, देविका टावर,
6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन 6441554, 6445971, 6414113
टेलेक्स : 031-71095

किस्त योजना का लाभ लीजिए

GOYAN/DRVP2288/HI/RE

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"अपने डॉक्टर से यह जानकर
मुझे बड़ी खुशी हुई कि
केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र
से सचमुच बालों का
झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ
जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३%में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

बालों का झड़ना रोकने का
प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कितनी पक्की डोर

अंततः चार विपक्षी दलों—लोकदल, जपा, कांग्रेस (स) और जनमोर्चा का एका हो ही गया. लेकिन समाजवादी जनता दल के ये घटक साथ चल पाएंगे? समस्याएं रहने से वी.पी. सिंह के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है. विपक्षी एका की रिपोर्ट:

आवरण कथा.....14

अपनों पर पराया हमला

इंका के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी कभी-कभी हदें लांघ जाते हैं. अरुण नेहरू की बेटी की सगाई रवि टिक्कू के बेटे के साथ हुई तो केसरी ने नेहरू-टिक्कू के खिलाफ आरोपों की बौछार कर दी. क्षुब्ध टिक्कू ने केसरी पर मानहानि का दावा ठोंक दिया.

आजकल.....26

एलान से आया तूफान

स्पेन के प्रधानमंत्री गोंजालेज़ ने जब यह धमाकेदार घोषणा की कि उनका देश वायुदूत के लिए भारत को 'कासा' विमान सप्लाई करेगा तो देश के उड्डयन हलकों में हलचल-सी मच गई. स्पेन की इस पेशकश से उपजे विवाद की अंदरूनी जांच-पड़ताल.

खास रपट.....46

कड़वे फैसले लेने की घड़ी

मुख्यमंत्री से केंद्रीय वित्तमंत्री बने शंकरराव चव्हाण ने महसूस कर लिया कि नई जिम्मेदारी मुश्किलों से भरी है. संसाधनों की कमी और बढ़ते घाटे के कारण स्थिति गंभीर हो रही है जिससे निपटना एक चुनौती है. इस स्थिति का विश्लेषण.

कारोबार.....52

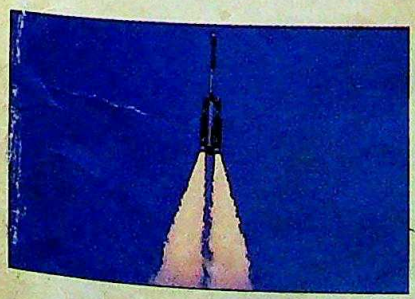

आशा-निराशा की आंखमिचौनी

पिछले महीने संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान जितनी तेजी से ऊपर उठा, लगभग उतनी ही तेजी से बंगाल की खाड़ी में जा गिरा. इस विफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों पर कड़ी टीका-टिप्पणी हुई है. आखिर विशाल वैज्ञानिक संस्थाएं किन रोगों से पीड़ित हैं?

खास रपट.....66

हाशिए पर खड़े लोगों की कथा

मीरा नायर की फिल्म 'सलाम बांबे' में रोजी-रोटी के लिए जद्दोजहद करते फुटपाथी बच्चों की वास्तविक तस्वीर है. इसे मई में कान फिल्मोत्सव में 'कैमेरा द ओर' पुरस्कार मिला. नायर से बातचीत और फिल्म में काम करने वाले फुटपाथी बच्चों पर रिपोर्ट.

सिनेमा.....76

अगले पन्नों पर

कसौटी.....8
राजरंग.....9
तेवर.....10
हिंदोस्तां हमारा.....11
बीता पखवाड़ा.....12
आवरण कथा
विपक्ष: हो गया गठजोड़, मगर
कितनी पक्की डोर?.....14
आजकल
पंजाब: नाजुक मोड़ पर नुकसान.....25
नेहरू खानदान: अपनों पर पराया हमला..26
दिल्ली: लापरवाही का कहर.....28
दार्जिलिंग: अमन की आहट.....31
गुजरात: होश में लाने का टेढ़ा उपाय.....32
पंजाब: रक्तबीज अभी मरा नहीं है.....34
मध्य प्रदेश: शौक भारी पड़ा.....35
मानसून: इंद्र मेहबान.....36
हरियाणा: कुओं में यमदूत.....38
बात पते की.....39
जम्मू: चुराई हुई जीत.....40
तमिलनाडु: अनूठी सरकारी दानशीलता....42
तमिलनाडु: बंटे हुए फिर बंटे.....44
खास रपट
वायुदूत: एलान से आया तूफान.....46
राज्य-दर्पण.....49
व्यापार चक्र.....51
कारोबार
अर्थव्यवस्था: कड़वे फैसले लेने की घड़ी.....52
डनलप: अनिश्चित भविष्य.....55
ईपी दवाएं: विकृति पर विजय.....56
वाणिज्य वार्ता.....58
खबरवालों की खैर.....59
रहन-सहन
नगालैंड: मुश्किलों से घिरी ममता.....60
स्वास्थ्य
स्तन कैंसर: रोग का रोना.....63
अपराध
तमिलनाडु: सनकी हत्यारे की शिनाख्त....64
उड्डयन
एअर इंडिया: महाराजा की सेवा में.....65
खास रपट
भारतीय विज्ञान:
आशा और निराशा की आंखमिचौनी.....66
इतिहास
नेहरू के पत्र:
भावनाएं, फूल और राजनीति.....72
सिनेमा
पति परमेश्वर: पेचीदे विवादों की उलझन75
सलाम बांबे:
हाशिए पर खड़े लोगों की कथा.....76
कला
लेटर्स टू ए डॉटर: संवेदनाओं का साझापन 79
खेलकूद
लॉन टेनिस: नई उम्र की नई फसल.....85
रंगमंच
चौराहा: कुव्यवस्था पर कटाक्ष.....87
किताबें.....88
चर्चित चेहरे.....96

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यादें धुंधला जाएँ...

ज़िन्दगी होती है छोटी-छोटी बातों का सिलसिला। जैसे जंगली रास्तों में सैर। या एक दूसरे के साथ चुराए गए दो पल। यही है वह सब जिससे बनती हैं यादें। यादें जो समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़िन्दगी भर अटल रहती हैं। जैसे कि हीरो साइकिल।

समय की कसौटी पर खरी, क्वालिटी का बेजोड़ नमूना। आज भी आप ऐसी हीरो साइकिलें देख सकते हैं जो गुणवत्ता का सबूत बनी पिछले दस से भी अधिक वर्षों से देश विदेश की सड़कों पर दौड़ रही हैं।

३२ वर्षीय कम्पनी – हीरो। २,२४,१०,००० से भी अधिक साइकिलों का उत्पादन। यकीनन विश्वास, गुणवत्ता और परम्परा का प्रतीक।

विशेषताओं का ऐसा संगम जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के ऐतिहासिक पृष्ठों में शामिल कर हीरो को दुनिया की नम्बर वन साइकिल होने की ख्याति दिलाई है। हीरो पर सवारी लीजिए – स्वयं को नम्बर १ महसूस कीजिए।

जीवन एक लम्बी डगर। हीरो हमसफर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हीरो का पार न पाएँ।

* हीरो जैट ५५ सै. मी.

दुनिया भर में नं० 1

1 HERO BICYCLES

* जैन्ट्स और लेडीज़ मॉडलों में उपलब्ध

हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना

हीरो अपनाएँ — नं० 1 होने का अनुभव पाएँ।

HC-NP-203

CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्राउन क्लासिक :
रंगीन टीवी की वो बेजोड तकनीक
जो दूसरों के लिए बनी प्रतीक

दो साल पहले क्राउन ने रंगीन टीवी टेक्नोलॉजी का एक नया अध्याय खोला। क्राउन क्लासिक के रूप में। और बनने लगे इसी आधार पर बाकी रंगीन टीवी। और क्यों नहीं? क्राउन क्लासिक एकमात्र ऐसा टीवी है जिसमें 17 निराली विशेषताएँ थीं, जैसे–ऑन/ऑफ टाइमर, कई आकारों में ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले, ऑटो चैनल सर्च इत्यादि, जिन्होंने भारतीय टीवी टेक्नोलॉजी को एक नए शिखर तक पहुँचाया। यह मुमकिन है कि, ये विशेषताएँ आज कुछ औरों ने अपना ली हों फिर भी निस्सन्देह इस अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखने वाला एकमात्र टीवी क्लासिक ही है। इसलिए रंगीन टीवी खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि, असल और नकल में फर्क क्या है! आखिर रूप और प्रतिरूप में कोई अन्तर होगा।

NO 1
CROWN-TV

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 2, अंक: 19, 1-15 अगस्त, 1988

प्रधान संपादक
अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक
प्रभु चावला

संपादकीय विभाग
जगदीश उपासने, अशोक कुमार
विजय क्रांति, ओम प्रकाश सराफ
अरविंद मोहन मिश्र

प्रोडक्शन
अनिल शर्मा, सुबाचन यादव
सुनील सैनी

■ **संपादकीय कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4. टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली.

■ **मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:** इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

■ **मुख्य विज्ञापन कार्यालय:** 28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया, बंबई.

■ **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325376, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली • फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास • 74/1 सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर • 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता. • कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता. • लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

नेपाल में 8 रुपए

सराहनीय प्रवृत्ति

महिला उद्यमियों की सफलता के सोपानों पर आवरण कथा 'कदमों के नए निशां' (31 जुलाई) पढ़कर तसल्ली-सी हुई कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं घर की चौखट लांघ तेजी से आगे बढ़ रही हैं. सरकार को भी चाहिए कि ऐसी महिलाओं को हर संभव सहायता और प्रोत्साहन दे.

—ऋतु खन्ना, बीकानेर (राज.)

■ इन महिलाओं के संघर्ष और सफलताओं ने साबित कर दिया है कि वे किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं हैं—न मेहनत करने में, न जिम्मेदारियां निभाने में. मौका मिले तो सफलता के एक के बाद दूसरे सोपानों को पार कर वे भी तेजी से शीर्ष पर पहुंच सकती हैं.

—संजय दुबे, राजेंद्र शर्मा, रायपुर (म.प्र.)

■ संविधान में बराबरी का दर्जा दिए जाने के बावजूद ज्यादातर महिलाओं को शिकायत रहती है कि करना तो वे भी कुछ चाहती हैं, पर उन्हें अवसर नहीं दिए जाते. लेकिन किरण मजूमदार, नलिनी शर्मा, शहनाज हुसैन और प्रभा खेतान की संघर्ष गाथा पढ़कर साबित हो जाता है कि जहां चाह हो, वहां राह भी बनती जाती है.

—दीपक मलिक, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

■ यह पढ़कर बेहद खुशी हुई कि हमारे देश की महिलाएं भी अब मेहनत और लगन से सफल उद्यमी बन देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं.

—रमण शाह, फरीदाबाद (हरियाणा)

■ पिछले दशक में देश की औद्योगिक क्रांति में अपना योगदान देने के लिए संकल्पवान, स्वतंत्र विचार की कर्मठ महिलाओं का एक समूह आगे आया है जिसने अपनी लगन और अध्यवसाय से प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है. आवरण कथा के माध्यम से तो आपने हजारों दूसरी महिलाओं को स्व-नियोजन और प्रतिष्ठा की जिंदगी जीने के लिए उद्यमी बनने की ही प्रेरणा दी है.

—मुकुटधारी अग्रवाल, भागलपुर (बिहार)

■ भारत जैसे विशाल देश में जहां व्यापार के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है और महिलाओं में शिक्षा के प्रसार से आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने से कौन रोक सकता है. बस जरूरत है कड़ी मेहनत और लगन की.

—रानो राकेश, हरदा (म.प्र.)

झूठा दावा

'कठिन राह राजनीति की' (31 जुलाई) पढ़ा. बीरबहादुर सिंह का यह कहना कि 'मैं नए मुख्यमंत्री के लिए समस्यामुक्त राज्य छोड़कर जा रहा हूं,' एकदम गलत है. बीरबहादुर ने राज्य में ऐसे हालात बना दिए थे कि आम जनता ही नहीं, कई विधायक भी उनके खिलाफ थे. ताजा उपचुनाव में इलाहाबाद में वोट कांग्रेस विरोधी नहीं बल्कि सच कहें तो बीरबहादुर विरोधी ही पड़े थे.

—विजयपाल सिंह, नैनीताल (उ.प्र.)

■ समस्यामुक्त नहीं, समस्यायुक्त राज्य छोड़ गए हैं बीरबहादुर सिंह. नारायणदत्त तिवारी और शरद पवार दोनों आलाकमान के विश्वासी मोहरे हैं. इनके कंधों पर इन राज्यों में इंका की जीत पक्की कराने का दायित्व कठिन ही नहीं, परीक्षनीय भी है.

—आर.एस. 'राजू', गया (बिहार)

अलगाववाद का आला

अरुणाचल प्रदेश में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव पर आपकी रिपोर्ट 'समाज को सलीब का सहारा' (31 जुलाई) पढ़कर लगता है कि धर्म परिवर्तन यदि इसी तरह जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब अरुणाचल प्रदेश से अलगाववाद का धुआं उठता दिखाई देगा. देश के जिस हिस्से में मिशनरियों का प्रभाव बढ़ा, वहीं से अलगाववाद की आवाज उठी. वनवासी यदि धार्मिक कर्मकांडों से मुक्ति पाने के लिए ही धर्म परिवर्तन करते हैं तो यह सरकार की कमजोरी है कि वह उन तक शिक्षा व विज्ञान नहीं पहुंचा सकी और उन्हें राष्ट्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की मुख्य धारा से नही जोड़ सकी.

—सुरेंद्र शर्मा, मारवाड़, (राज.)

■ आपके लेख ने ईसाई मिशनरियों के दुष्चक्र का पर्दाफाश कर दिया है. समय रहते यदि सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं. सरकार को सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मिशनरियों की गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए

—यतींद्र प्रताप सिंह चंदेल, कन्नौज (उ.प्र.)

लापरवाही का नतीजा

केरल में हुई रेल दुर्घटना का 'दिल दहला देने वाला हादसा' (31 जुलाई) रेल मंत्रालय की लापरवाही व रखरखाव के अभाव का ही परिणाम है. कई रेल मार्ग, पुल व डिब्बों के बारे में चेतावनी देने के बावजूद रेल मंत्रालय के कान पर जूं नहीं रेंगी. दुर्घटना के बाद रेलमंत्री के इस्तीफे का नाटक जले पर नमक छिड़कने वाला ही लगता है.

—चेतन, जोधपुर (राज.)

■ लेख इस हृदयविदारक दुर्घटना का सही चित्र प्रस्तुत करता है. दुर्घटना का कारण चाहे जो भी रहा हो, यह सरकार की लापरवाही का एक जबरदस्त उदाहरण है. अब तक निरापद समझी जाने वाली रेल-यात्राएं भी अब सुरक्षित नहीं रहीं.

—प्रदीप अग्रवाल, झांसी (उ.प्र.)

■ जब भी रेल या किसी और तरह की दुर्घटना होती है तब प्रशासन की चारों ओर से आलोचना होने लगती है. सरकार भी तब सुधार के बड़े-बड़े दावे करती है पर समय के साथ सब भुला दिया जाता है. बाद में सरकार जितना पैसा अनुग्रह राशि के रूप में बांटती है उतना यदि रखरखाव पर खर्च करे तो दुर्घटनाएं होंगी ही नहीं.

—विपिन, सुलतानपुर लोदी (पंजाब)

वर्चस्व की लड़ाई

'तने तमंचों की तान' (31 जुलाई) पढ़ा. मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद और शिवचंद्र झा के बीच ताजा रस्साकशी बताती है कि इन्हें बिहार की समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं. दिलचस्पी है तो सिर्फ अपना वर्चस्व बनाए रखने में. ऐसे में बिहार का भविष्य क्या होगा, इसका सहज अंदाज लगाया जा सकता है.

—नरेंद्र नागवंशी, पटना (बिहार)

गंभीर चेतावनी

■ 'दहशत की दस्तक' (31 जुलाई) पढ़कर लगता है कि भारत सरकार एड्स के संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं. इस लापरवाही के कारण जहां देश भर में यह रोग फैल रहा है, वहीं आम जनता एड्स के लक्षणों से परिचित भी नहीं है. यदि सरकार ने इस दस्तक को गंभीरता से नहीं लिया तो अमेरिका व यूरोप की भांति भारत में भी यह रोग अपने पांव जमा लेगा.

—विजय कुमार तंवर, जोधपुर (राज.)

सरकार दोषी

'मजहबी जुनून' (31 जुलाई) में आपने लिखा है कि दंगों के लिए मुस्लिम लीग किसी हद तक दोषी है. यह आरोप सही नहीं है. हकीकत तो यह है कि ज्यादा दोष सरकार का है जो वोट के लिए सांप्रदायिकता की खाई बढ़ा रही है. इलाहाबाद में हुई हिंसा इसका ताजा उदाहरण है.

—सईद अहमद त्यागी, तलहेड़ी बुजुर्ग (उ.प्र.)

■ मुस्लिम लीग हमेशा ही धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपना उल्लू सीधा करती आई है. बहुत पहले केरल के मल्लपुरम् में उसने यही किया, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में भी यही किया और मुर्शिदाबाद में तो उसके लिए सुनहरा मौका था. ज्योति बसु सरकार को चाहिए कि इन फिरकापरस्तों से सख्ती से निपटे न कि मसले पर अपनी राजनैतिक रोटी सेंके.

—हर्षनारायण पांडेय, रायपुर (म.प्र.)

उदार बनें

वेश्याओं के अभागे बच्चों पर लेख 'बदनामी बन गई बाधा' (31 जुलाई) पढ़कर मन क्षोब से भर गया. इस माहौल में पलकर तो लड़कियां वेश्या और लड़के अपराधी ही बनेंगे और यह चक्र चलता ही रहेगा. इसलिए सरकार और समाज दोनों को ही चाहिए कि थोड़ा उदार रवैया अपनाएं और इन्हें सम्मानित जीवन जीने में मदद करे क्योंकि इसका परिणाम अंततः समाज को ही भुगतना पड़ता है.

—ओमवत्स शर्मा, नई दिल्ली

सच बर्दाश्त नहीं

'दावों की कलई खुली' (31 जुलाई) से ऐसा लगता है कि दूरदर्शन दूसरे के मुंह पर पट्टी बांधकर उसकी आलोचना करना चाहता है. 'न्यूजलाइन' तथा 'जनवाणी' का बंद कर दिया जाना और घोषित की गई फिल्म 'न्यू देहली टाइम्स' के प्रसारण को रोक दिया जाना इसी का प्रमाण है कि सच का पर्दाफाश करने वाले कार्यक्रम दूरदर्शन को बर्दाश्त नहीं होते.

—कपिल, होशंगाबाद (म.प्र.)

साख का सवाल

उपचुनावों के नतीजों के विश्लेषण पर आवरण कथा 'कांग्रेस (इ) : मुश्किलों का कहर बरपा' (15 जुलाई) से पता चलता है कि इंका अब जनता का विश्वास खो बैठी है. 1984 में उसे जो भारी बहुमत मिला था, वह इंदिरा गांधी की मौत से उपजी सहानुभूति के अस्थायी आधार पर टिका था. इन साढ़े तीन वर्षों में साबित हो गया है कि यह सरकार बस घोटाले करने और फिर उन पर परदा डालने में ही माहिर है.

—नारायण, डाल्टेनगंज (बिहार)

■ राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद कहा था कि उनका मंत्रिमंडल छोटा और सुयोग्य व्यक्तियों का होगा तथा उसमें उपमंत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा. किंतु 42 महीनों में 24 बार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन यही साबित करता है कि योग्य व्यक्तियों की तलाश अभी भी जारी है. छह उपमंत्रियों सहित सबसे बड़ा 62 सदस्यीय मंत्रिमंडल उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट करता है.

—संदीप सवाई 'दीपू', इंदौर (म.प्र.)

■ राजीव गांधी का बार-बार मंत्रिमंडल में फेरबदल उनकी अपरिपक्वता ही उजागर करता है. इस कारण नेताओं का ज्यादा समय अपनी कुर्सी बरकरार रखने के चक्कर में दिल्ली दरबार में ही बीतता है. यदि यही हाल रहा तो इलाहाबाद चुनाव परिणाम कल पूरे देश का परिणाम भी बन सकता है.

—अविनाशचंद्र मिश्र, गोरखपुर (उ.प्र.)

■ लगता है कि उपचुनावों के नतीजों ने सत्ता पार्टी के मनोबल को काफी गिरा दिया है. पार्टी की गिरती साख बचाने के लिए राजीव अब पुराने कांग्रेसियों की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं. आडवाणी का यह कथन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल कूड़ेदान बनकर रह गया है, सही ही लगा. राजीव मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल कर रहे हैं जिनसे राज्य नहीं संभले.

—यश कमल, बूंदी (राज.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बार-बार के फेर-बदल से मंत्रिपद की महत्ता काफी घटी है. फिर भी देखना यह है कि आने वाले 18 महीनों में बिखरा विपक्ष संगठित होता है या हताश राजीव कांग्रेस की छवि का धुंधलापन दूर कर पाते हैं, क्योंकि भारतीय मतदाता साबित कर चुका है कि अपने वोट का सदुपयोग करना उसे आता है.

—कल्याणदास माहेश्वरी, बड़नगर (म.प्र.)

■ आवरण कथा में ही 'कोई सूरत उन्हें नहीं भाती' पढ़कर लगा कि विपक्षियों के अहं की टकराहट उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी. अगर हर विपक्षी नेता प्रधान-मंत्री ही बनना चाहेगा तो विपक्ष कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगा और यदि आ भी गया तो पहले की तरह असफल रहेगा.

—महेश भाई मस्ताना, सागर (म.प्र.)

कुछ तो सबक लें

कसौटी के अंतर्गत 'दूध का दूध, पानी का पानी' (15 जुलाई) पढ़ा. आपने सही लिखा है कि राजीव गांधी का रिकार्ड इतना दागदार हो चुका है जिसे संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट साफ नहीं कर सकती. अब जब जनता ने इलाहाबाद में राजीव गांधी को अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो उन्हें कुछ तो सबक लेना चाहिए.

—किशोर नागपाल, रेवाड़ी (हरियाणा)

■ इलाहाबाद चुनाव परिणाम यह सिद्ध करता है कि आम जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है. लेकिन न तो उसे सक्षम एवं सुदृढ़ नेता मिलने का विश्वास है, और न ही एक झंडा, एक नारे तले विपक्ष के एक बने रहने की गारंटी. सत्तारूढ़ पार्टी इतनी दागी हो चुकी है कि कितनी भी कोशिश करे, बेदाग होना मुश्किल है. **—कृष्णकांत,** रांची (बिहार)

लाजवाब पत्रकारिता

'द हिंदू' के 'लाजवाब कर देने वाले तथ्य' (15 जुलाई) ने सरकार की कोशिशों को जहां नाकाम किया है, वहीं करार समेटने के रूप में भुगतान किए गए धन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है. जिस सचाई की लीपापोती के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी गई थी, आखिर एन. राम ने उसे बेनकाब कर ही दिया. पत्रकारिता जगत में ऐसे संपादकों की ही अब आवश्यकता है.

—बयाबंत, वाराणसी (उ.प्र.)

■ 'द हिंदू' का संपादक मंडल और उनकी जेनेवा संवाददाता प्रशंसा के पात्र हैं. ऐसे ही कुछ प्रतिभावान व्यक्तियों के बल पर भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का अस्तित्व बना हुआ है अन्यथा सरकारी मशीनरी ने तो पत्र-कारिता को सदा रौंदा, कुचला ही है.

—अजीत विक्रम सिंह, लखनऊ (उ.प्र.)

■ लाजवाब कर देने वाले तथ्य प्रकाशित कर 'द हिंदू' ने सरकार के सभी दावों और संसदीय समिति के निष्कर्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं. अब तक सरकार ने इस अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, यही हैरानी की बात है.

—सुशील मदान, नई दिल्ली

भावी पीढ़ी को क्या देंगे

'धमाकों से थमी धड़कनें' (15 जुलाई) पढ़ा. आतंकवादियों द्वारा ढाए गए कहर ने समूचे पंजाब को स्तब्ध कर दिया है. आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं इस बात की सूचक हैं कि आतंकवादियों के हौसले कितने बढ़े हुए हैं, ऐसे में इंस्पेक्टर और सिपाहियों के तबादले या उन्हें निलंबित करने से कुछ नहीं होगा (जैसा कि देवीलाल ने किया). जरूरत इस बात की है कि सुरक्षा प्रबंधों और खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया जाए.

—विक्रम शाह ठाकुर 'सुमन', कुम्हारी (म.प्र.)

■ लेख और साथ छपी तस्वीर देखकर सचमुच ही धड़कनें थम गईं. आखिर हम इस देश को क्या बनाने जा रहे हैं. आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? आतंकवाद? हिंसा? क्या वह कभी यकीन करेगी कि इसी देश में कभी महात्मा गांधी जैसे शांति के दूत ने जन्म लिया था.

—भरत गोस्वामी, पुणे (महाराष्ट्र)

सरकार भी कुछ करे

मिजो बागियों पर आपकी रिपोर्ट 'जीवन को मिला नया मकसद' (15 जुलाई) अच्छी लगी. अब चूंकि मिजो बागी सामाजिक जीवन जीने लगे है, सरकार को चाहिए कि वह मिजो समझौते की शर्तों को जल्द से जल्द पूरा करे.

—राजीव रतन केसरी, आरा (बिहार)

तिकड़मी 'संन्यासी'

'जान आफत में' (15 जुलाई) रिपोर्ट ने आंध्र के संन्यासी मुख्यमंत्री एन.टी. रामराव के एक और षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है. एन.टी. रामराव शायद भारत के अब तक के सबसे चालाक मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने सत्ता पर कब्जा जमाए रखने और प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने तिकड़म किए हैं, शायद ही किसी नेता ने किए होंगे. अपने चमचों द्वारा स्वयं पर असफल हत्या का प्रयास करवाकर जनता की सहानुभूति बटोरना तो एक मिसाल भर है.

—राजेश कुमार 'मेहरड़ा', बीकानेर (राज.)

चंदा उगाही में अव्वल

टीवी सीरियल 'रामायण' की लोक-प्रियता पर रिपोर्ट 'राम नाम की लूट है' (15 जुलाई) पढ़कर लगा कि यह लूट राम नाम की नहीं, बल्कि रामायण की है. यदि राम नाम की लूट होती तो देश में रामराज्य की स्थापना न हो जाती? लेकिन रामायण सिर्फ देखी जाती है, उससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती.

—पुरुषोत्तम गुप्ता, राजगढ़ (म.प्र.)

■ रामभक्तों की तादाद लाखों में है, और राम नाम पर 'चंदा' इकट्ठा करने वाले भी. इस बार चंदा इकट्ठा करने में सागर साहब बाजी मार ले गए हैं. वे जानते हैं कि भारतीय जनता निश्चित रूप से धर्म के मामले में भावुक और आदिकाल से ही धर्म के नाम पर पैसा लुटाने की आदी है.

—सुशील डी. विनायकिया, खंडप (राज.)

सेवा पर उज्र क्यों

'जिहादी पर जुल्म' (15 जुलाई) रिपोर्ट पढ़ी. डॉ. जैक प्रेगर के प्रति राज्य सरकार का रवैया देखकर हैरानी हुई. केंद्र और राज्य सरकारें खुद इन गरीबों को न तो रोजगार दे पाती हैं, न ही स्वास्थ्य सुविधाएं. फिर उन्हें डॉ. प्रेगर की निःस्वार्थ सेवा पर क्या आपत्ति है? सरकार उन्हें भारत की नागरिकता नहीं देना चाहती तो न दे पर उन्हें देश से बाहर भेजकर जनता को इन सुविधाओं से वंचित क्यों करना चाहती है? **—सुनील शुक्ला,** कानपुर (उ.प्र.)

■ एक विदेशी डॉक्टर द्वारा भारत की गरीब जनता को इतनी सस्ती सेवाएं उप-लब्ध कराने की उदारता जितनी सराहनीय है, केंद्र और राज्य सरकार की उन्हें बाहर खदेड़ने की जिद इतनी ही हैरान करने वाली लगती है. **—सुरेश पारीक,** चुरु (राज.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

पर्यटन प्रेम बनाम घरेलू सच

प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हालत कुछ-कुछ भंवरे जैसी है. एक देश से दूसरे वे घूमते ही रहते हैं. लेकिन भंवरा तो फूलों के रस चूस भी लेता है, प्रधानमंत्री के तो जैसे पांव भी जमीन पर नहीं पड़ते. अभी हाल ही में वे चार देशों की यात्रा महज 10 दिनों में करके लौट आए. है न अजूबा! पिछले 50 महीनों में उन्होंने जिन 52 देशों का दौरा किया उनमें से प्रत्येक की राजधानी में वे शायद डेढ़ दिन से ज्यादा नहीं ठहरे.

भारी जनसमर्थन के बीच जब वे गद्दीनशीन हुए थे तब खुद को विश्व बिरादरी से परिचित कराने के लिए की गई उनकी यात्राओं को कुछ हद तक जरूरी भी समझा गया था. तब देश में उत्साह का जो माहौल था और क्षेत्रीय ताकत बनने के जो कूटनीतिक इरादे थे उनके मद्देनजर उनकी यात्राएं तर्कसंगत भी लगी थीं. लेकिन आज जबकि देश में फिर वही उथलपुथल जैसा माहौल है, इस तरह की यात्राएं खीझ और गुस्सा पैदा करती हैं. उनकी यात्राओं का अनुपात जिस तेजी से बढ़ता है, प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं को उतना ही नुकसान पहुंचता है. लेकिन कोई प्रधानमंत्री अगर हर दसवें दिन देश से बाहर रहे (एक अनुमान के मुताबिक) और विदेश यात्राओं की उपलब्धियों का ही ढोल पीटता रहे तो सवाल उठेंगे ही.

रेखाचित्र: अजीत मैनन

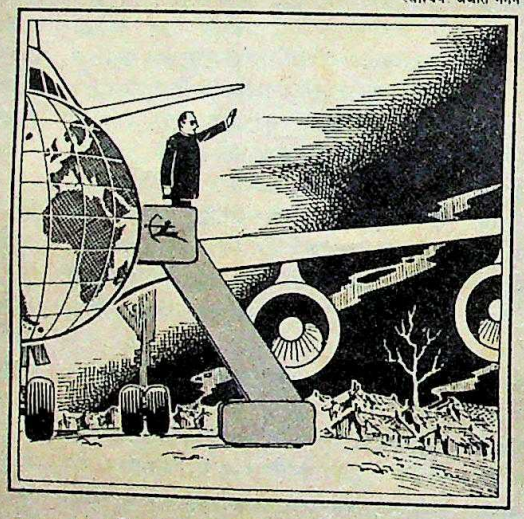

इन यात्राओं की उपलब्धियां तो होंगी, क्योंकि आपसी लेनदेन में और क्या होगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उपलब्धियां समय की कसौटी पर खरी साबित होंगी विशेषकर आज जबकि मिखाइल गोर्बाचेव के पदार्पण से शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है? राजीव ने अमेरिका की यात्रा करके राष्ट्रपति रेगन से जो कथित व्यक्तिगत रिश्ता कायम किया उसकी भारत-अमेरिका संबंधों में नया मोड़ कहकर प्रशंसा की जा रही थी. लेकिन बाद के महीनों में दोनों देशों के रिश्ते सुधरने के बजाय बिगड़ते ही गए. इसका प्रमुख सबूत तो यही है कि रेगन सरकार ने न केवल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों की ओर से आंखें मूंद रखी हैं बल्कि अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी के बावजूद पाकिस्तान को हथियारों के नए जखीरे देने की मंजूरी भी दे दी है. और तो और, वह भारत के इन आरोपों को भी मानने को तैयार नहीं दिखती कि पाकिस्तान पंजाब में सिख अलगाववादियों को शह दे रहा है.

व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ हो जाएगा कि रूस और अमेरिका के बीच सुलह के नए दौर के बाद इन दो महाशक्तियों के बीच कड़ी बनने की भारत की भूमिका भी अप्रासंगिक हो गई है. फिर, रूस में हो रहे फेरबदल के मद्देनजर भारत की अहमियत उसके लिए कितनी रह जाएगी यह भी विचारणीय है. और बड़ा सच तो यह है कि देश में जो माहौल है उसके चलते भारत बहुत हौसले के साथ दुनिया के सामने खड़ा होने की हैसियत में नहीं है.

इन तमाम तथ्यों के मद्देनजर राजीव के दौरों और उनकी उपलब्धियों के स्थायित्व पर सवाल उठाना लाजिमी लगता है. हंगरी जैसा देश एक तो विदेश नीति के मामले में बहुत आजाद नहीं है. दूसरे, आपसी व्यापार-वाणिज्य के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. तुर्की, जॉर्डन और सीरिया के पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं. इस्लामी समुदाय के प्रति भी ये देश भावनात्मक रूप से जुड़े हैं. भारत इन्हें पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति बदलने के लिए राजी कर पाएगा इसकी संभावना कम ही है.

सबसे असंगत बात तो यह है कि राजीव अपने इन दौरों में आम तौर पर भारत के इन आरोपों को उछालते रहे हैं कि पाकिस्तान पंजाब में दखलंदाजी कर रहा है. या फिर वे अफगानिस्तान में कट्टरवादी शासन की स्थापना के खतरे, निरस्त्रीकरण, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद जैसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हैं. इस तरह वे भारत पर उन्हीं आरोपों को— द्विपक्षीय मसलों को दुनिया भर में उछालना— निमंत्रण देते हैं जिन्हें वे पाकिस्तान पर लगाते रहे हैं. ऐसे में भारत पाकिस्तान पर किस मुंह से आरोप लगा सकता है कि वह कश्मीर मसले को दुनिया भर में उछाल रहा है. इस देश का मतदाता यह जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के इन दौरों का मकसद क्या है और इनकी जो उपलब्धियां हैं वे क्या इन दौरों पर होने वाले खर्च और निर्णायक क्षणों में देश से प्रधानमंत्री की गैरहाजिरी के खतरे की तुलना में बीस पड़ती हैं.

लगता है राजीव के सलाहकारों की नजरों से ये अहम मुद्दे छूट गए हैं. राजीव के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि उनकी छवि एक लापरवाह, अनावश्यक तेजी दिखाने वाले व्यक्ति की बन गई है. तथाकथित उपलब्धियों के पीछे दोहरे मतलब छिपे हों तो बात नहीं बन सकती. कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो आज स्पेन का दौरा बहुत जरूरी नहीं था. रक्षा या दूसरे तरह के करार मंत्री या अधिकारी स्तर पर किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं. स्पेन के दौरे से हासिल? स्पेनी प्रधानमंत्री द्वारा वायुदूत को करोड़ों रुपए के विमान देने के करार की घोषणा. मजे की बात यह कि वायुदूत ने स्पेनी कासा विमान को अपनी जरूरतों की सूची में शामिल तक नहीं किया था.

जाहिर है ऐसी बातों से राजीव के पर्यटन प्रेम पर प्रश्न उठेंगे और उन पर आरोप लगेगा कि वे विदेशों से टुच्ची सहायता के लिए घरेलू समस्याओं की उपेक्षा करते रहे हैं. पंजाब में हत्याओं, गोरखालैंड के गोरखधंधे, श्रीलंका में गतिरोध और तमाम ऐसी खबरों के बीच किसी राजप्रासाद में चाय की चुस्कियां लेते राजीव और सोनिया के चित्र जब अखबारों में छपते हैं तो कल्पना में वही ऐतिहासिक बिंब उभरता है— रोम जल रहा है और उसका बादशाह नीरो मौजमस्ती कर रहा है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संतोष का असंतोष

● केंद्रीय गृह राज्यमंत्री संतोष मोहन देव का सितारा इन दिनों पार्टी में और सरकार में भी बुलंदी पर है. लेकिन पिछले दिनों जब वे रक्षा राज्यमंत्री की हैसियत से पार्टी के किसी काम के सिलसिले में कलकत्ता गए थे तो कुछ मुश्किल में फंस गए. उन्होंने एक जगह इंका कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि

वाममोर्चा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वे सड़कों पर उतर आएं. संतोष के इस बयान पर माकपा कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए. उन लोगों ने मंत्री महोदय की कार को बीच रास्ते में घेर लिया और उस पर पथराव किया.

इस वारदात से नाराज संतोष ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु से कहा कि वे तुरंत इसकी जांच करवाकर रिपोर्ट उन्हें भेजें. पर बसु ने टका-सा जवाब दे दिया कि वे केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह हैं, उनके प्रति नहीं. बसु ने शायद कुछ जल्दबाजी कर दी थी. उनके इस बयान के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और संतोष को गृह राज्यमंत्री बना दिया. बिल्ली के भाग से छींका टूटा. संतोष तुरंत बसु की गरदन पर सवार हो गए. सबसे पहले उन्होंने बूटा सिंह को राजी किया और उस वारदात को लेकर बसु को एक तीखी चिट्ठी भिजवाई. फिर उन्होंने बसु को परेशान करना शुरू किया. उन्होंने उनसे बूटा सिंह के पत्र का जवाब मांगना शुरू कर दिया. माकपा सूत्रों का कहना है कि आग संतोष ने ही सुलगाई थी इसलिए मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं ताकि संतोष अपनी ही करनी का मजा चख सकें.

गरिमा का प्रश्न

● मास्को में भारत महोत्सव की समाप्ति के समारोह में राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निजी संदेश क्या पढ़ा कि देश-विदेश के कूटनीतिक और राजनैतिक हलकों में कइयों की भवें टेढ़ी हो गईं. कूटनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और अब ऐसा करके वेंकटरामन ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को ही धूमिल कर दिया.

राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष और एक दल का नेता. वरीयता क्रम में राष्ट्रपति ही ऊपर होता है. इसलिए राष्ट्रपति का काम प्रधानमंत्री की मुसाहिबी करना नहीं हो सकता. दरअसल राष्ट्रपति जब विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनके साथ एक मंत्री (मिनिस्टर इन वेटिंग) को भी भेजा जाता है जो वक्त जरूरत प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ता है. कूट-

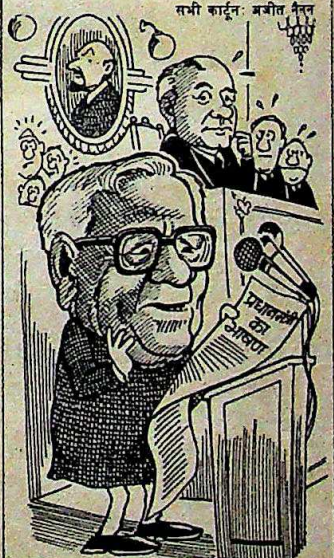

नीतिक प्रेक्षकों को ज्यादा सदमा इस बात से पहुंचा है कि अपने स्वतंत्र विचारों और परंपराओं का सख्ती से पालन करने के लिए मशहूर राष्ट्रपति अपने ही पद की गरिमा के निर्वाह में चूक कैसे कर बैठे. वैसे, अटकलें जारी हैं कि राष्ट्रपति से यह चूक अनजाने में हो गई या प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव के कारण.

याद बताए...

● केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बीर बहादुर सिंह को अपने उत्तर प्रदेश की और लखनऊ के खूबसूरत और आरामदेह दफ्तर की याद कुछ ज्यादा ही सताती है. कितनी बेतकल्लुफी से वे वहां सोफे पर पांव चढ़ाकर तोंद सहलाते हुए, उंगलियां चटखाते हुए गप्पें मारा करते थे. और कहां यह दिल्ली के संचार

मंत्रालय का दफ्तर! यहां का मिजाज ही कुछ अलग है. इतनी तकल्लुफ और नफासत भला देसी बीर बहादुर को कहां भाये. यहां तो सलीके की पोशाक और आगंतुकों के साथ नफासत भरे व्यवहार की जरूरत होती है. और मुसीबत तो तब होती है जब उन्हें आगंतुक हस्तियों को पांचतारा होटलों में भोज देना पड़ता है, उनकी मेजबानी करनी पड़ती है.

मामला तब और भी उलझ जाता है जब बीर बहादुर को लगता है कि केंद्रीय मंत्री का उनका काम ज्यादा चुनौती भरा नहीं है. पहले हफ्ते जब वे अपने नए दफ्तर में गए तो एक अरसे से जमा पड़ी फाइलों आदि को उन्होंने चंद घंटे में ही निबटा दिया. उन्होंने वहां आने वाले एक व्यक्ति से कहा, "कौन कहता है कि यह काम कठिन है. इस काम के लिए तो हर रोज चार घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं. उस आदमी के लिए तो यह कुछ भी नहीं जिसने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की सरकार चलाई हो." सो आजकल उनके पास समय की कोई कमी नहीं. इस समय का सदुपयोग वे अपने पुराने स्टाफ में करते हैं, यानी राज्य के उन राजनीतिकों के साथ अड्डेबाजी जो अभी भी उनके आसपास मजमा लगाए रहते हैं.

रिकार्ड दर रिकार्ड

● केंद्रीय गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो एक नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में है. इसने आधुनिकीकरण की तीन साल की एक योजना बनाई है. इस योजना के तहत देश भर में होने वाले अपराधों के सारे रिकार्ड पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और केंद्रीकृत कर दिए जाएंगे.

इसके लिए ब्यूरो 42 करोड़ रुपए का भारी-भरकम ठेका देने जा रहा है. हाल के वर्षों में सरकार ने कंप्यूटरीकरण के जो ठेके दिए हैं उनमें यह सबसे बड़ा ठेका होगा. पिछले पखवाड़े तक इसके लिए बोलियां लग रही थीं. ठेका पाने वाली कंपनी को सॉफ्टवेयर की व्यवस्था तो करनी ही होगी, जिलों में लगाने के लिए 500 सुपर माइक्रो कंप्यूटर भी देने होंगे. इसके अलावा 100 सुपर मिनी कंप्यूटर और कम-से-कम दो मेनफ्रेम कंप्यू-

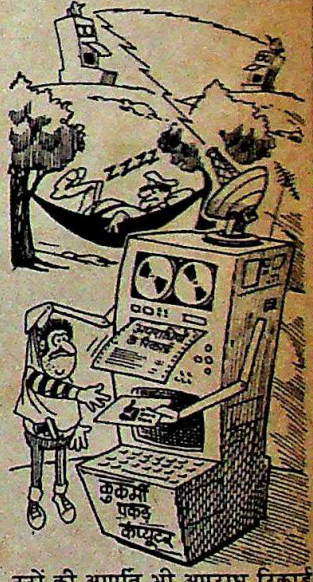

टरों की आपूर्ति भी अपराध रिकार्ड ब्यूरो को करनी पड़ेगी.

अपराध रिकार्ड ब्यूरो की इस योजना के तहत अपराधियों की उंगलियों के निशान इकट्ठे कर कंप्यूटरों में रखे जाएंगे ताकि वक्त जरूरत अपराधियों की शिनाख्त के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क पर इन निशानों को देश के किसी भी कोने में उपलब्ध कराया जा सके.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपकी चहेती पत्रिका
आपके दरवाज़े पर
न खरीदने का झंझट...
न खत्म होने का डर

इस सुविधा का लाभ उठाइए.
आपनी चहेती इंडिया टुडे
घर बैठे – नियमित पाइए.
न खरीदने जाने की ज़रूरत...
न अंक खत्म होने का डर,
इंडिया टुडे
समय से पहुंच जाए आपके घर !

बस कूपन भर कर भेज दीजिए,
देर मत कीजिए !

नाम _____
डाक पता _____

मूल्य वार्षिक रु. 120/-
भुगतान का माध्यम – चैक/मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट
कृपया चैक निम्नलिखित नाम पर बनाएं और इस पते पर भेजें
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सर्कुलेशन डिपार्टमेंट थौमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ नं. 60, दिल्ली मथुरा रोड,
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

MILESTONES/IT/120

रविशंकर, इंडियन एक्सप्रेस

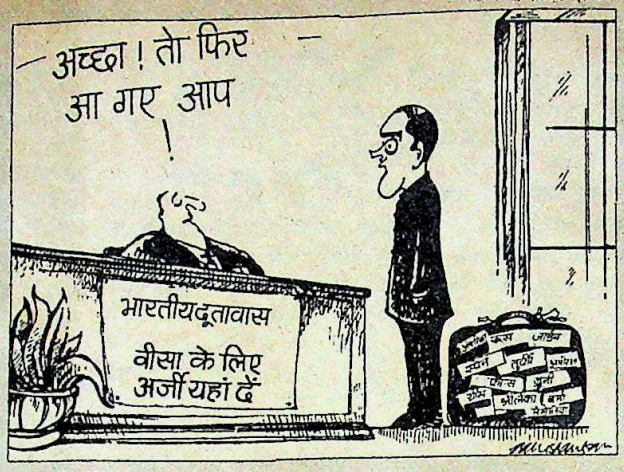

● मेरा तो विदेश में कोई गुप्त या खुला खाता नहीं है. आपको अधिकारपत्र देकर मैं यह कह रहा हूं. श्री सीताराम केसरी महोदय! ऐसा ही अधिकारपत्र आप उनसे लीजिए जो विदेश में गोपनीय खाते के मसले पर नंगा हो चुके हैं.

■ **अरुण नेहरू,** कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी को पत्र में

● मैं आज भी कहता हूं कि अरुण नेहरू सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं हैं.

■ **सीताराम केसरी,** *नवभारत टाइम्स*

● वह (जनमोर्चा) भी कांग्रेस के दलदल की काई है.

■ **ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद,** *नई दुनिया*

● बहुगुणा तो रुकावट (विपक्षी एकता में) नहीं हैं. चंद्रशेखर की बात जनता पार्टी जाने... मैं कोई मुनीम नहीं हूं जो सबके बही-खाते खोलता फिरूं. ■ **देवीलाल,** *हिंदुस्तान*

● किसी 'गुलाम' (गुलाम नबी आजाद) के आरोपों का जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता.

■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *प्रोब*

● आशीर्वाद देना तो हमारा खानदानी पेशा है. हमारे यहां जो भी आता है, हम उसे आशीर्वाद देते हैं.

■ **कमलापति त्रिपाठी,** उनसे मिलने गए जनमोर्चा नेताओं को आशीर्वाद देने पर

● कमलापति त्रिपाठी को कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देना चाहिए.

■ **अटल बिहारी वाजपेयी,** *जनसत्ता*

● मुझे आज तक कोई भ्रष्ट पत्रकार नहीं मिला. हां, कोई दुष्ट पत्रकार कभी मिला हो. मगर भ्रष्ट? नहीं, कभी नहीं.

■ **अजीत वाडेकर,** *सोसायटी*

● अगर वे (विश्वनाथ प्रताप सिंह) सोचते हैं कि हम फिल्मवाले मदारी हैं तो क्या वे खुद भी मदारी नहीं हैं?

■ **अरुण गोविल,** *इलस्ट्रेटेड वीकली*

● दर्शकों को जूठन परोसने में मेरा कोई विश्वास नहीं.

■ **देवानंद,** *हिंदुस्तान*

● मैं सुंदर भी नहीं, टेलेंटेड भी नहीं. अगर मैं फिल्मों में अब तक टिकी हूं तो उसकी वजह है तकदीर, सिर्फ तकदीर.

■ **दिपल,** *धर्मयुग*

● मेरी सभी सहयोगी अभिनेत्रियां जितने प्रेमी रखती हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए मैं तो बस कुछ ही रखती हूं.

■ **रेखा,** *रविवार*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गाय का अन्याय

■ परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के भाग्य का फैसला उनके हाथों लिखी गई उत्तर पुस्तिकाओं से होता है. लेकिन यदि उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाने से पहले ही चोरी हो जाएं, गुम हो जाएं या

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

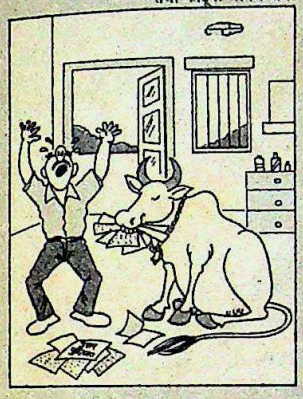

फिर किसी गाय के पेट में चली जाएं तो तय है कि मामला विधानसभा तक तो जाएगा ही.

पिछले पखवाड़े महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा ही एक मामला सवाल-जवाब के दौरान सामने आया. सवाल पूछे जाने पर शिक्षामंत्री ने स्वीकार किया कि उत्तर पुस्तिकाओं में धांधली के कारण 460 विद्यार्थियों के परिणाम रुके हुए हैं. इनमें से कुछ मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने बदल दिए गए थे और कुछ में से अतिरिक्त पन्ने उड़ा दिए गए थे. लेकिन एक मामले में खुराफात की जड़ एक गाय पाई गई. कम-से-कम कापियां जांचने वाले अध्यापक ने शिक्षा विभाग को जो वजह बताई उससे तो सारा कसूर गऊ माता का ही नजर आता है. पता चला कि रसायनशास्त्र की उर्दू पुस्तिकाओं की जांच का काम जिन अध्यापक महोदय को सौंपा गया था उनकी गाय को पुस्तिकाएं ऐसी पसंद आईं कि वह उन्हें चट कर गई. बेचारे ने एक साधु की शरण ली ताकि गायब हुई पुस्तिकाओं का मामला निबट सके. लेकिन उधर बेचारे शिक्षामंत्री विधायकों को यह जवाब नहीं दे पा रहे थे कि अध्यापक महोदय गौशाला में कापियां जांच रहे थे या फिर गाय उनके पढ़ने के कमरे में आराम फरमाने गई थी?

बेताल तबादले

■ स्कूलों का नया सत्र शुरू होने के साथ ही अध्यापकों के तबादलों का मौसम भी शुरू हो जाता है और विद्यार्थियों को नए साल की किताबों के साथ ही साथ भांति-भांति के नए अध्यापकों के चेहरे भी देखने को मिलने लग जाते हैं. पिछले पखवाड़े महाराष्ट्र के अहमद नगर के एक स्कूल के विद्यार्थी भी अपने हेडमास्टर साहब का इंतजार ही करते रहे मगर वे पहुंचे नहीं. गनीमत थी कि वे नहीं पहुंचे. पहुंच जाते तो शायद विद्यार्थी उन्हें देखकर ठहर भी नहीं पाते. बहरहाल, छुट्टियां खत्म होने के बाद जब स्कूल में नए हेडमास्टर साहब नहीं पहुंचे तो बात शिक्षा विभाग तक पहुंची. वहां जांच करने पर पाया गया कि क्लर्क महोदय ने वहां के लिए ऐसे हेडमास्टर के तबादले का फरमान जारी कर दिया था जिन्हें भगवान के घर गए हुए कई महीने बीत चुके थे.

लेकिन शिक्षा विभाग के क्लर्कों ने अपना कमाल इस इकलौते मामले तक ही सीमित रखा हो, ऐसी बात नहीं. उनकी कलमों ने ऐसे-ऐसे जलवे दिखाए कि शिक्षा विभाग के आला अफसर दंग रह गए. जिले में इस साल किए गए 531 तबादलों में से एक और मामले में एक अध्यापिका के बजाय उसके बेरोजगार पति को तबादले का आदेश जारी करते हुए उसे

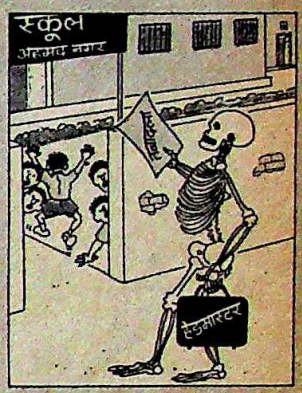

हिदायत दी गई कि वह अमुक कन्या विद्यालय में हाजिर हो. और एक दूसरे मामले में तो एक अध्यापक के बजाय उसके मकान मालिक को ही तबादले का हुक्म सुना दिया गया.

मुआवजे के लिए मरा

■ नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वे काफी आकर्षक हैं. लेकिन क्या इन मुआवजों के लिए कोई खुद को मरा हुआ भी घोषित कर सकता

है? विचित्र किंतु सच है कि ऐसा भी होता है.

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस विभाग ने ऐसा ही एक मामला पकड़ा जिसमें एक सिपाही ने विभाग को अच्छा-खासा चूना लगा दिया था. किस्सा यह है कि रिटायर होने से 15 दिन पहले एक सिपाही अपनी बची हुई छुट्टियां लेकर घर चला गया. उसके घर पहुंचने पर परिवार के लोगों ने विभाग की दरियादिली का फायदा उठाने की योजना बनाई. सिपाही के पुत्र ने विभाग के अफसरों को तार देकर सूचित किया कि दिल का दौरा पड़ने से उसके पिता जी की मृत्यु हो गई है. अफसरों ने बाद में इस तार और नगर निगम के मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर कर्मचारी के परिवारवालों को 20 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर कर दी और पारिवारिक सुरक्षा कोष से 50 हजार रु. की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी भी दे दी. पिता की मृत्यु पर सामाजिक मुहर लगाने के लिए बेटे ने अपना सिर भी मुंडवा लिया और पिता जी की तेरहवीं का आयोजन भी कर डाला. लेकिन पिता जी की एक गलती ने तब सारा भांडा फोड़ दिया जब उन्हें रेलवे प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हुए उनके एक अफसर ने पकड़ लिया.

मुलजिम बंदर

■ जयपुर पुलिस के रिकार्ड में मुलजिम के बतौर अब एक बंदर ने भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है. एक समाचार के अनुसार यहां के एक परिवार ने पुलिस में रपट दर्ज कराई है कि एक बंदर उनके घर से लगभग 30 हजार रु. के गहने चुराकर चंपत हो गया.

रपट के अनुसार इस परिवार की एक महिला अपने गहनों समेत एक शादी में शरीक हुई. देर रात घर लौटने पर वह इतनी थकी हुई थी कि उसने गहने उतारकर एक रुमाल में बांधे और पोटली तिपाई पर रखकर सो गई. अगली सुबह आदत के अनुसार मुहल्ले के बंदर जल्दी ही जाग गए. भोजन तलाशी मुहिम पर निकले बंदरों की टोली में से एक की निगाह उस पोटली पर पड़ी और वह उसे ले उड़ा. रपट के अनुसार एक बच्चे ने बंदर को पोटली उठाते देखा था. बाद में जब गहनों की खोज होने लगी तब लोगों को समझ में आया कि बंदर केवल रुमाल नहीं बल्कि गहने भी ले उड़ा था. खोज-खबर लेने पर लोगों को एक पेड़ के नीचे रुमाल तो मिल गया पर उसमें बंधे गहने गायब थे. पुलिस फिलहाल यह तय नहीं कर पा रही है कि बंदर ये गहने किसी बंदरिया को रिझाने के लिए ले गया या उसने उन्हें बेकार समझकर फेंक दिया और गहने किसी और के हाथ लग गए.

फिलहाल पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि चोर बंदर की शक्ल दूसरे बंदरों से मिलती है. इसलिए असली मुलजिम को पकड़ने में वह अपने आप को लाचार पा रही है.

संकलन: विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जवाब मांगते सवाल

कहानी उसी शाश्वत त्रासदी की है. बदलते हैं तो सिर्फ पात्र और स्थान. भारत की समस्याएं इतनी संगीन हो चुकी हैं कि पखवाड़े बीतते जाते हैं, कहीं कुछ खास नहीं बदलता. कल अगर सत्ता दल की ओर से जली-कटी सुनाने की 'जिम्मेदारी' के.के. तिवारी संभाले हुए थे तो आज सीताराम केसरी उनके उत्तराधिकारी बने बैठे हैं जिन्हें अरुण नेहरू और रवि टिक्कू के परिवारों की रिश्तेदारी में खोट नजर आ रही है. कल अगर करार ललडेंगा के साथ हुआ था तो आज घीसिंग की सेहराबंदी की तैयारी है जिनका नाम अभी दो साल पहले तक शायद ही कोई जानता था. और इसी तरह कल अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस हड़ताल पर थी तो आज गुजरात की.

सत्ता दल की ओर से जली-कटी उगलने की जिम्मेदारी आज सीताराम केसरी संभाल रहे हैं

बदलती हैं अगर कुछ, तो वे हैं मान्यताएं. और इसके साथ ही एक बात जो अहम होती जा रही है वह है—जवाबदेही. इन सारी स्थितियों के लिए जवाबदेही किस पर थोपी जाए? देश की राजधानी में हैजे की महामारी फैलती है. 150 से ज्यादा लोग मरते हैं और इसके लिए जवाबदेह तमाम हलके पल्ला झाड़ते नजर आते हैं. नौकरशाही तो इसे महामारी मानने से भी इनकार करती है. जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता.

वित्तमंत्री शंकरराव चव्हाण के सिर कांटों का ताज है क्योंकि संसाधन की भीषण कमी में विकास के पहिये धंस सकते हैं

उधर विपक्षी दलों को लगता है एहसास हो गया है कि एक हो जाना ही श्रेयस्कर है. नेतृत्व देने के लिए एक लोकप्रिय नेता भी मिल गया है. लेकिन कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं एकता के प्रयासों को ठेंगा दिखा रही है. सबको पता है एकता की राह में रोड़ा बनने वाले ये कौन लोग हैं. तो फिर इन्हें रास्ते से हटाया क्यों नहीं जा रहा? जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती?

प्रधानमंत्री विदेशों का एक और तूफानी दौरा करके लौट आते हैं. लेकिन इन यात्राओं से भारतीय जनता को क्या हासिल होने वाला है इसका कोई जिक्र नहीं किया जाता. एक वक्त था कि उनकी इन यात्राओं पर कोई सवाल नहीं उठाता था. आज कई सवाल उठ रहे हैं. तब अखबारों में फब्तियां नहीं कसी जातीं थीं. आज कसी जा रही हैं (एक टिप्पणी मुलाहिजा फरमाइए: "हो सकता है यह सच न हो लेकिन विश्वस्त सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री राजीव गांधी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं"). ये सवाल, ये फब्तियां इसलिए क्योंकि जवाबदेही के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ती जा रही है.

सभी रेखाचित्र: पिअली दत्त गुप्ता

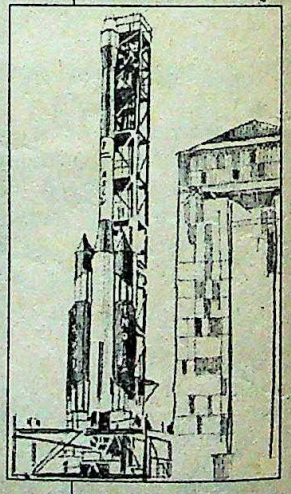

श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष उपग्रह के प्रक्षेपण की असफलता को विज्ञान की पहेलियों में उलझा कर नहीं निबटाया जा सकता

वित्त मंत्रालय के धुरंधरों का तो कहना है कि अर्थव्यवस्था उम्दा दौर में है. लेकिन अफसोस कि सच कुछ और है. वित्तमंत्री शंकरराव चव्हाण ने कांटों का ताज पहन लिया है. संसाधन की भीषण कमी में विकास के पहिये धंस सकते हैं. जाहिर है आला नौकरशाहों की गणनाओं में खोट है, लेकिन गुमनामी के परदे के पीछे वे महफूज पड़े हैं. उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं.

विपक्षी उम्मीदवार द्वारा अनशन के बावजूद यह जवाब देनेवाला कोई नहीं कि चुनाव प्रक्रिया क्यों कमजोर हो रही है

श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष उपग्रह के प्रक्षेपण की लगातार दूसरी बार असफलता को विज्ञान की पहेलियों में उलझा करके निबटाया नहीं जा सकता. निश्चित रूप से कहीं कोई बड़ी खामी है जिसका पैसे या प्रतिभा से खास ताल्लुक नहीं है. कौन जवाब देगा कि भारत के इस 'अति महत्वाकांक्षी' अंतरिक्ष कार्यक्रम में बेहिसाब पैसा क्यों फूंका जा रहा है.

उधमपुर संसदीय उपचुनाव में हुई धांधली के तमाम सबूतों, विपक्षी उम्मीदवार द्वारा चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने अनशन करने के बावजूद इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है कि लोकतंत्र की नींव (चुनाव प्रक्रिया) कैसे कमजोर हो रही है? इन चुनावों में धांधली करने वाले ठग कौन हैं? कौन इन्हें पैसे देता है?

लेकिन ऐसे टेढ़े सवाल अब बड़ी शिद्दत और तेजी से पूछे जाने लगे हैं. शायद इसलिए क्योंकि आम चुनाव नजदीक हैं. घटनाएं और मुद्दे अब अचानक अहम और नाजुक बन गए हैं. जनता की प्रतिक्रियाएं तीखी होती जा रही हैं, सहिष्णुता का बांध टूटता जा रहा है. इसमें छिपे संकेत जितने विश्वनाथ प्रताप सिंह और विपक्ष के उनके साथियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उतने ही राजीव और सत्ता दल के लिए भी.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कॉफ़ी की शान...

सर्वोत्तम 100% शुद्ध इन्स्टैंट कॉफ़ी का शानदार स्वाद। ख़ास चुने हुये कॉफ़ी बीन्स से तैयार और भरपूर फ़्लेवर युक्त यह लाजवाब कॉफ़ी आप सब का दिल जीत लेगी।

आज ही गोल्ड कैफ़े लाइये और अपने परिवार के साथ आनन्द लीजिए। आप स्वयं कहेंगे "वाह! कॉफ़ी का बेमिसाल अन्दाज़!"

GOLD CAFE

सर्वोत्तम 100% शुद्ध कॉफी

इन्सटेंट कॉफी

RAJAN D SESHAN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विपक्षी गठजोड़ मगर कितनी

वे सब के सब किसी ऊबाऊ नौटंकी के कलाकार सरीखे दिखते थे. दो-टूक बात कहने वाले देवीलाल बिस्तर पर पड़े-पड़े ही अपने सिपहसालारों को निर्देश दे रहे थे. चिकने-चुपड़े अजीत सिंह कभी यहां तो कभी वहां फिरकनी-से चक्कर काट रहे थे. अपनी खिचड़ी दाढ़ी के लिए मशहूर दुबले-पतले चंद्रशेखर अलग ही खिचड़ी पकाने में व्यस्त थे जबकि बीजू पटनायक के जिम्मे भोजवार्ताएं आयोजित करने का काम था. और इस पूरे नाटक के नायक विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने कंप्यूटर पर विपक्षी एकता के जोड़-घटाव का पेचीदा सवाल हल करने में लगे हुए थे.

लगता था कि ये सारे कलाकार विपक्षी एकता के कथानक वाले इस नाटक को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे. पर अचानक पटाक्षेप होने से जरा भर पहले हुई घटनाओं ने सबको चौंका दिया.

हफ्तों तक कहा-सुनी की कसरत कर चुकने के बाद 26 जुलाई को चार मध्यमार्गी पार्टियां—जनता, लोकदल, कांग्रेस (स) और जनमोर्चा 15 अगस्त तक विलय कर लेने पर सहमत हो गईं. नई पार्टी का नाम भी खासा बड़ा है—समाजवादी जनता दल.

एक लिहाज से यह विलय 1977 की भावना के पुनरुत्थान का प्रतीक है और अगर बात सिरे चढ़ गई तो अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों से पहले प्रचंड आंधी का रूप ले सकता है. लेकिन इन पार्टियों की खिचड़ी अभी पूरी तरह पक नहीं पाई है. पिछले महीने की तीखी वार्ताओं को यदि संकेत मानें तो विपक्ष के नए मसीहा वी.पी. सिंह को इंका के किसी भरोसेमंद विकल्प की हैसियत पाने के लिए कई अड़चनें पार करनी होंगी. एक तरफ जहां नई पार्टी के नेतृत्व का सवाल मुंह बाये खड़ा है, वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ रिश्तों की समस्या भी उन्हें हल करनी है. सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस गठजोड़ की डोर कितनी पक्की साबित होगी?

ऐसी उलझनों और पहेलियों की जानकारी वी.पी. सिंह से ज्यादा किसी को नहीं. इन दो हफ्तों में वे विपक्ष के वरिष्ठ सहयोगियों से करीब 3000 घंटे तक मगजमारी करते रहे. अपने पर्सनल कंप्यूटर में वी.पी. सिंह ने तीन स्पष्ट रेखाएं खींची हैं ताकि भ्रांतियों के घालमेल से कोई मतलब निकाला जा सके. उन्होंने विपक्ष को तीन भागों में बांटा है. एक, मुख्य नेताओं का गुट; दो, मझोले स्तर के नेताओं का गुट और तीन, बाकी बचे हुए विपक्षी नेता.

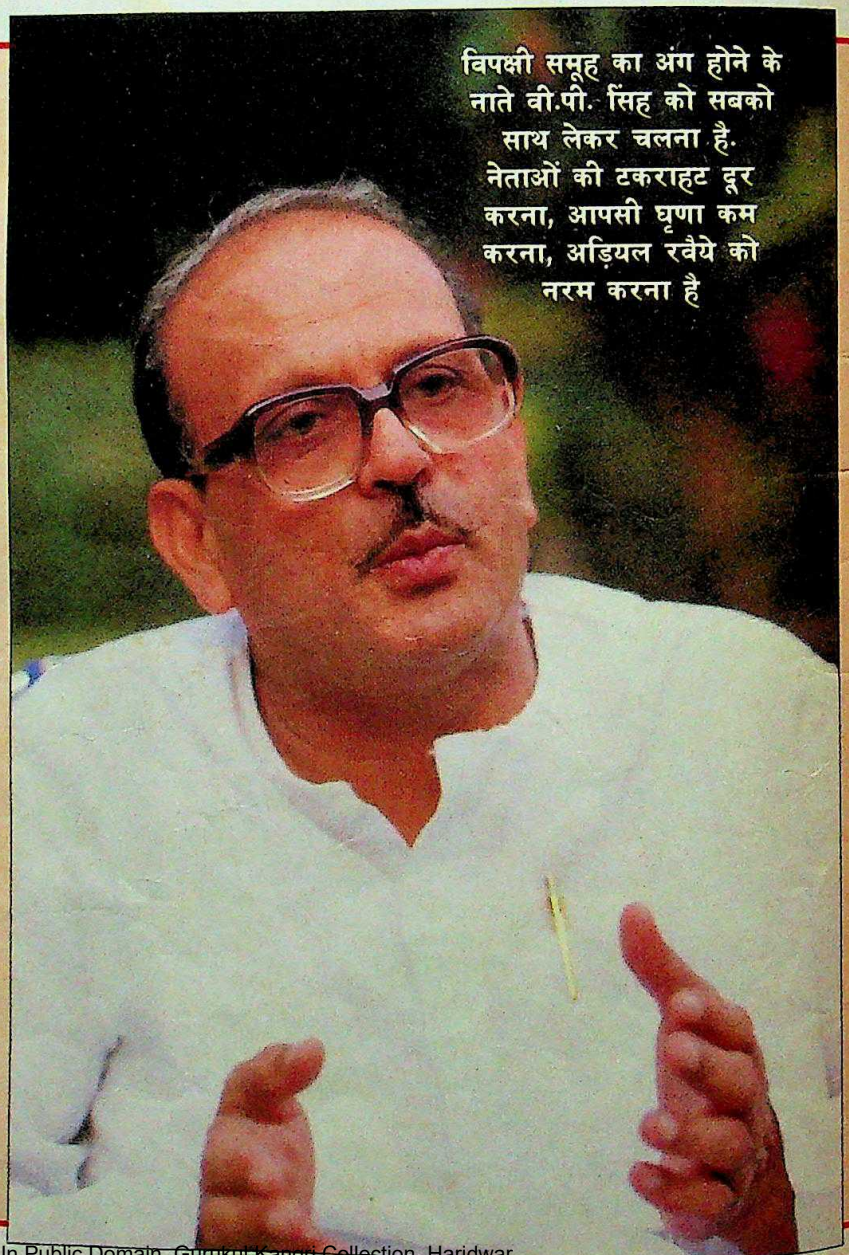

विपक्षी समूह का अंग होने के नाते वी.पी. सिंह को सबको साथ लेकर चलना है. नेताओं की टकराहट दूर करना, आपसी घृणा कम करना, अड़ियल रवैये को नरम करना है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पक्की डोर?

मुख्य गुट में चंद्रशेखर, रामकृष्ण हेगड़े, नंदमूरि तारक रामराव, देवीलाल, अजीत सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, हेमवतीनंदन बहुगुणा और ज्योति बसु जैसे नेता हैं. इन नेताओं के सक्रिय समर्थन के बिना विपक्षी एकता नहीं हो सकती. दूसरे गुट में भैरों सिंह शेखावत, बीजू पटनायक, मधु लिमये, मधु दंडवते, मुलायम सिंह यादव, एम. करुणानिधि और प्रफुल्ल महंत जैसे नेता हैं. तीसरे गुट में छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य जो किसी भी तरह की विपक्षी एकता के विरोधी हैं.

यह विडंबना ही है कि विपक्षी एकता कराने की जिम्मेदारी—मौका, संयोग, मान-मनौवल, भावनात्मक दबाव और खुशामद के जरिये—वी.पी. सिंह पर पड़ी, जिन्होंने पहले कभी राजनैतिक पद न लेने का संकल्प किया था. और यहां तक कि वे इलाहाबाद उपचुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे. यानी विरोधाभासों से भरे वी.पी. सिंह संतुलन

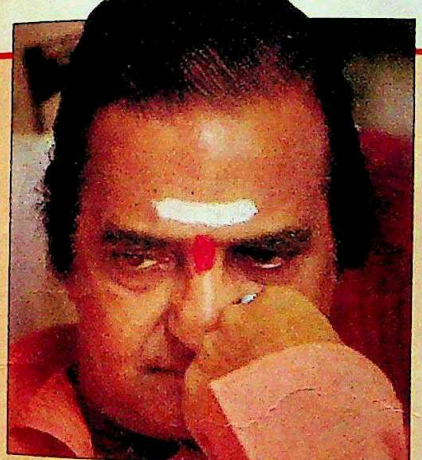

नंदमूरि तारक रामराव ऐसी व्यवस्था के पक्ष में हैं जिसमें उनकी भूमिका वी.पी. सिंह जितनी ही महत्वपूर्ण हो

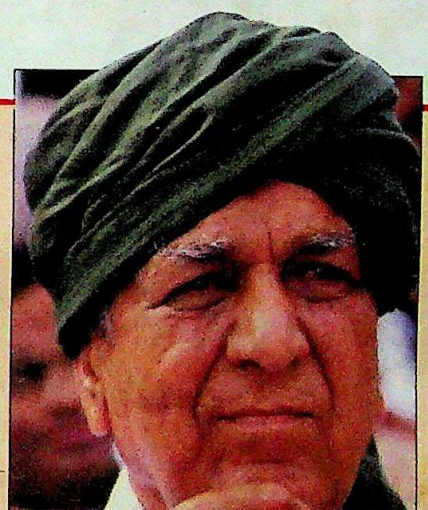

एकता में अहम भूमिका निभाने वाले देवीलाल नई व्यवस्था में अजीत सिंह को महत्वपूर्ण पद देने के खिलाफ हैं

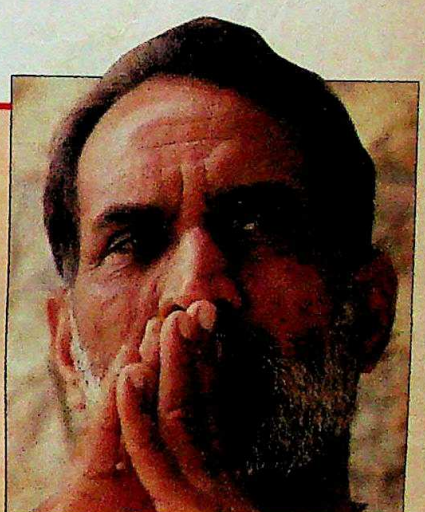

चंद्रशेखर चुनाव तक नेतृत्व का फैसला टालना चाहते हैं ताकि वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री न बनें

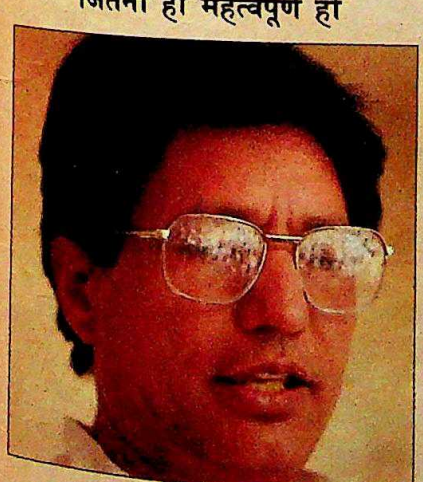

अजीत सिंह को नई व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद का भरोसा दिया गया तो वी.पी. सिंह को नेता के रूप में मंजूर कर सकते हैं

रामकृष्ण हेगड़े को भरोसा हो जाए कि चंद्रशेखर से उन्हें कोई खतरा नहीं है तो वी.पी. सिंह को अपना नेता मानते रहेंगे

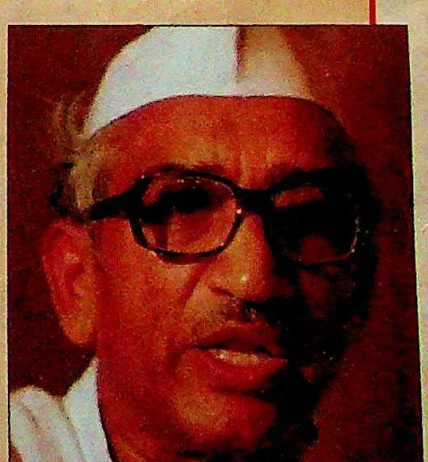

हेमवतीनंदन बहुगुणा ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें वे उ.प्र. में टिकटों के बंटवारे में निर्णायक भूमिका निभा सकें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब मशहूर रंगीन टी वी की दुनिया में

चैम्पियनों का चैम्पियन

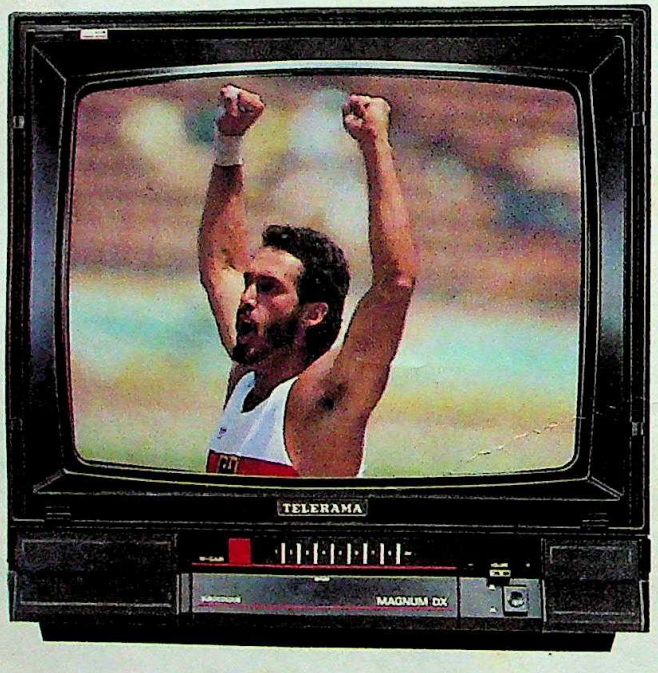

TELERAMA
MAGNUM DX HI-GAIN

दो साल की गारंटी पिक्चर ट्यूब सहित

नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय रूप। सम्पूर्ण काला और फिनिश चिकनी। हू-ब-हू रंग सहित जीवन्त तसवीर। दो-तरफा स्पीकर—जिसमें क्रॉसओवर नेटवर्क तकनीक की वजह से आवाज़ भी जानदार। कम्प्यूटर की मदद से तैयार, इसलिए काम की क्वालिटी लाजवाब और निर्भरयोग्यता की भी पूरी निश्चयता। दूर हो या पास-हाई-गेन की देन स्पष्ट और शानदार तसवीर। मैगनम DX यूरोकलर टी वी—देखने में आराम, रखने में शान।

टेलेरामा मैगनम DX हाई-गेन टी वी। यकीन कीजिये—यही है चैम्पियनों का चैम्पियन!

It's the smart choice

अपने करीबी डीलर के पास इसके दमखम की जाँच कीजिये...
सचमुच, यह सबको मात देगा।

TELERAMA AUTHORISED SERVICE CENTRE FOR ITT COLOUR TVs

3337A2

CC-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

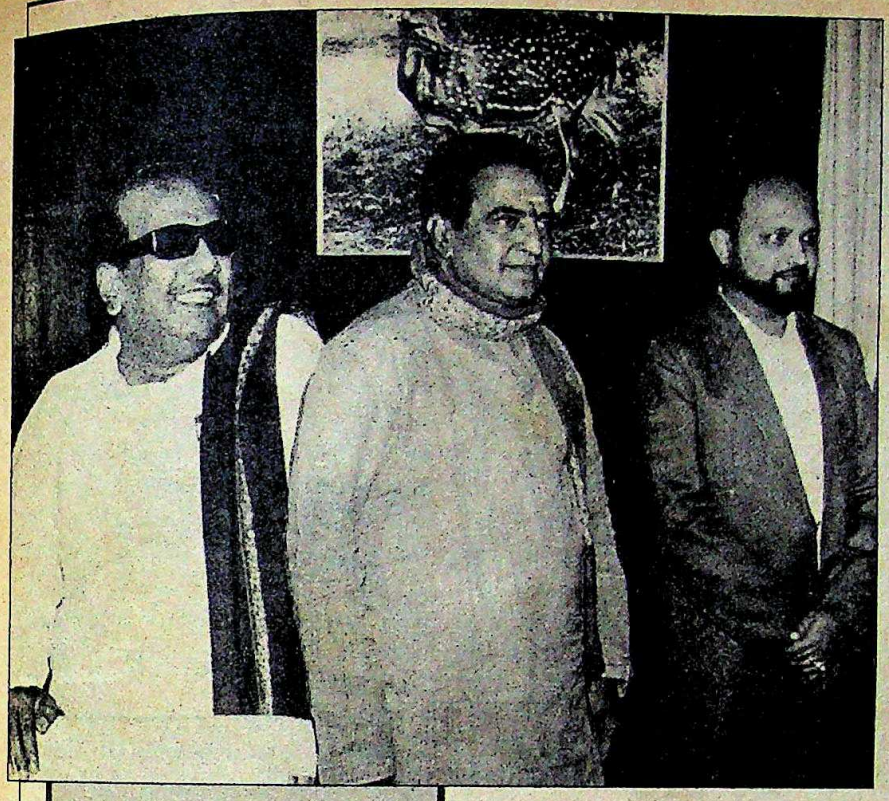

प्रफुल्ल महंत, रामराव और करुणानिधि जैसे क्षेत्रीय नेता अपने-अपने क्षेत्रों में करीब 100 लोकसभा सीटों के भाग्य का फैसला कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं

बनाने का काम कर रहे हैं. यदि इसमें वे सफल हो जाते हैं तो उससे देश के राजनैतिक परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है.

और आज अपनी ही विसंगतियों से जूझने वाले इसी व्यक्ति के बारे में माना जा रहा है कि वह विपक्षी खेमे का एकमात्र ऐसा राजनीतिक है—विपक्ष की भारी उम्मीद भी—जो गैर इंका पार्टियों के बीच के झगड़े और उनकी अंदरूनी गुटबाजी को खत्म कर सकता है. वी.पी. सिंह को जब उन्हीं की पार्टी से बाहर फेंक दिया गया था तब किसी संगठन या पार्टी ने उनका समर्थन तक नहीं किया था. लेकिन उन्होंने जब ऊंचे पदों पर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाना शुरू किया और पूरे देश में उनकी सभाओं में भारी भीड़ खिंचने लगी तब विपक्षी पार्टियों का ध्यान उनकी तरफ गया.

वी.पी. सिंह के लिए जन समर्थन और उनकी क्षमताओं के बारे में जो भी थोड़ा-बहुत संदेह विपक्षी दलों के भीतर रह गया था, वह इलाहाबाद उपचुनाव के बाद खत्म हो गया. हाल के लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी की शर्मनाक पराजय के बाद ही विपक्षी पार्टियों को सद्बुद्धि आई और उनके नेता एकता पर गंभीरता से बातचीत करने लगे. सात में से चार लोकसभा सीटों पर इंका की पराजय और एक सीट (उधमपुर) पर उसकी संदिग्ध और बहुत कम अंतर से विजय ने संकेत दे दिया कि प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी की लोकप्रियता घट रही है. इसका इतना ही महत्वपूर्ण संदेश यह भी था कि संयुक्त विपक्ष के समर्थन से वी.पी. सिंह राजीव के नेतृत्व को कड़ी चुनौती दे सकते हैं.

कांग्रेस (स) के नेता और लोकसभा के जाने-माने सदस्य के.पी. उन्नीकृष्णन कहते हैं, "वी.पी. सिंह को यह भूमिका निभानी ही है. विपक्ष में वे अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें विपक्षी पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भरोसा हासिल है." लेकिन इसके उलट विचार वाले लोकदल महासचिव बुद्धप्रिय मौर्य जैसे दूसरे नेता भी हैं. मौर्य कहते हैं, "वी.पी. सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता."

अब एक-दूसरे की महत्वाकांक्षाओं की टकराहट दूर करना, घायल अहं को शांत करना, आपसी घृणा कम करना, आहत भावनाओं को सहलाना, अड़ियल रवैये को नरम करना, गलतियां माफ करना और कड़वी बातों को भूल जाना और यह सब निर्विकार और अनथक भाव से करना—वी.पी. सिंह के लिए आज यही सबसे बड़ी चुनौती है. वी.पी. सिंह विपक्ष के विरोधाभासों से भी वाकिफ हैं. विपक्षी नेताओं ने इलाहाबाद उपचुनाव के बाद महसूस किया था कि वे अब वी.पी. सिंह के बिना नहीं रह सकते और अब जबकि वी.पी. सिंह उनके बीच हैं, उनको लगता है कि वे उनके साथ नहीं रह सकते. मसलन एकता वार्ता के चरम पर पहुंचने पर मुख्य गुट के कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा जताए गए इरादों और राजनैतिक आग्रहों को ही लें:

► पूर्व जपा अध्यक्ष चंद्रशेखर. वे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सिर्फ इसलिए दावा करते हैं कि उन्होंने देशव्यापी पदयात्रा की जिसमें उन्होंने अपने ट्रस्टों के लिए विशालतम रकम इकट्ठी की. विपक्षी एकता के लिए प्रतिबद्ध होने के बावजूद वे सभी दलों के जनता पार्टी में विलय पर जोर देते रहे. वे चाहते हैं कि नई विपक्षी पार्टी के नेतृत्व पर अगले लोकसभा चुनाव तक कोई अंतिम फैसला न किया जाए, शायद इस उम्मीद में कि वी.पी. सिंह को प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने से रोका जा सके. ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं कि अंततः उन्हें एकता प्रयासों से दरकिनार कर दिया गया.

► हेमवतीनंदन बहुगुणा. लोकदल का यह तेजतर्रार अध्यक्ष भी वी.पी. सिंह के नेतृत्व का विरोधी है. वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें वे उत्तर प्रदेश में टिकटों के वितरण में निर्णायक भूमिका निभा सकें. वे हमेशा से विरोधाभासों से भरपूर रहे हैं. हालांकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के विरोधी हैं लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम के साथ उनकी गाढ़ी छनती है.

► जपा अध्यक्ष अजीत सिंह. उनका दुर्भाग्य यही रहा है कि वे चंद्रशेखर पर पूरी तरह से आश्रित हैं. वी.पी. सिंह के प्रति उनकी नापसंदगी छिपाए नहीं छिपती. लेकिन यदि उन्हें नए ढांचे में कोई सम्मानपूर्ण जगह देने का भरोसा दिया गया तो वी.पी. सिंह को नेता के रूप में मंजूर कर सकते हैं.

► हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल. हालांकि उन्होंने वी.पी. सिंह को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है लेकिन वे चाहते हैं कि उन्हें सामूहिक नेतृत्व की निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाए रखा जाए. अजीत सिंह को कोई भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडियन एक्सप्रेस

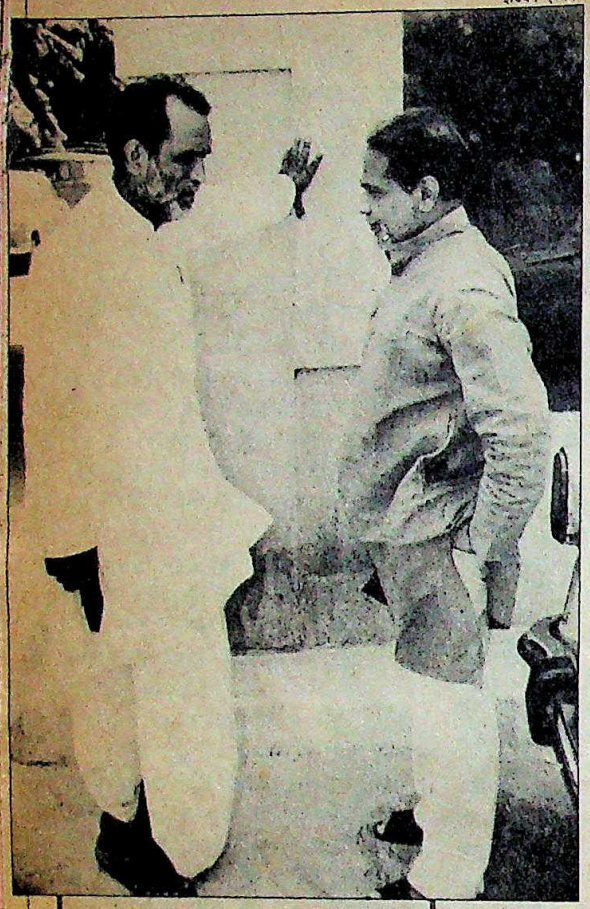

रामकृष्ण हेगड़े और चंद्रशेखर के बीच नेतृत्व के मामले पर रस्साकशी ने कर्नाटक में जनता पार्टी सरकार को तो हिलाकर रख ही दिया, विपक्षी एकता की राह में रोड़े भी अटकाती रही

महत्वपूर्ण पद देने के पूरी तरह खिलाफ हैं.

► कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े. जब तक उन्हें भरोसा रहेगा कि चंद्रशेखर से उन्हें कोई खतरा नहीं है, वे नए ढांचे में वी.पी. सिंह को अपना नेता मानते रहेंगे.

► आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव. वे ऐसी व्यवस्था के पक्ष में हैं जिसमें उनकी भूमिका वी.पी. सिंह जितनी ही महत्वपूर्ण हो.

अंतर्विरोध सिर्फ इन नेताओं तक ही सीमित नहीं. यहां तक कि अपेक्षाकृत अनुशासित पार्टियां भी नहीं जानती थीं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. मसलन:

जनमोर्चा: ताज्जुब की बात है वी.पी. सिंह की अपनी रसोई के बर्तन भी आपस में टकरा रहे हैं. हालांकि उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया जा रहा लेकिन रामधन जैसे उनके सहयोगी चंद्रशेखर या अजीत सिंह को कोई भी महत्व देने के विरोधी हैं. दूसरी तरफ अरुण नेहरू और आरिफ मुहम्मद खां नई पार्टी में भाजपा को शामिल किए जाने के विरोधी नहीं हैं लेकिन विद्याचरण शुक्ल जैसे नेता इसके सख्त खिलाफ हैं.

असम गण परिषद: यह भी अपनी क्षेत्रीय पहचान बनाए रखने के पक्ष में है. लेकिन परिषद वी.पी. सिंह को अपना नेता मानने के लिए तैयार है बशर्ते इस पर आम सहमति हो.

द्रविड मुनेत्र कडगम: यह संघीय पार्टी बनाने के पक्ष में है जिसमें उसे और तमिलनाडु को प्रमुख भूमिका दी जाए. इस पार्टी को वी.पी. सिंह को नेता मानने में कोई आपत्ति नहीं.

भारतीय जनता पार्टी: इसने स्पष्ट कर दिया है कि वह न तो किसी दूसरी पार्टी में अपना विलय करेगी और न ही किसी ऐसी सरकार में शामिल होगी जिसमें कम्युनिस्ट होंगे. लेकिन यह पार्टी वी.पी. सिंह के नेतृत्व और उनके साथ चुनावी तालमेल करने के खिलाफ नहीं है.

माकपा और भाकपा: कम्युनिस्ट भी विलय के खिलाफ हैं और उस सरकार में शामिल नहीं होंगे जिसमें भाजपा होगी. (साथ वाली रिपोर्ट देखें) ये पार्टियां मुद्दे पर आधारित एकता चाहती हैं और भाजपा को किसी भी तरह के चुनावी तालमेल से अलग रखने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं.

और इस बेतुके माहौल में ही एकता की तुरही बजाने वाले नेताओं को अपनी भूमिकाएं निभानी थीं. फिर भी, वी.पी. सिंह चार मध्यमार्गी पार्टियों—लोकदल, जनता, कांग्रेस (स) और जनमोर्चा को एक एकीकृत पार्टी की शक्ल में लाने में सफल हो ही गए. इस पार्टी का नाम होगा—समाजवादी जनता दल, जिसके औपचारिक गठन की घोषणा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाएगी. इसका झंडा लोकदल का होगा और इसके बीच में जनता पार्टी का प्रतीक 'चक्र में हलधर किसान' होगा.

चारों केंद्रीय पार्टियों के विलय का फैसला तीन घंटे की बैठक के बाद लिया गया. बैठक में देवीलाल, अजीत सिंह, विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू, के.पी. उन्नीकृष्णन और रामकृष्ण हेगड़े ने भाग लिया. बहुगुणा और चंद्रशेखर पूर्वानुमान के मुताबिक बैठक में नहीं आए. दरअसल, विलय के मुद्दे पर विशेष जोर दिया था देवीलाल ने. उन्होंने एक हफ्ते पहले ही विलय के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी थी. फिर उन्होंने अनिच्छुक नेताओं को राजी करने के लिए कभी उन्हें समझाया-बुझाया तो कभी डांटा-फटकारा. देवीलाल और हेगड़े के लिए यह विलय उनकी व्यक्तिगत विजय भी है. उन्होंने अपनी ही पार्टी के दिग्गजों, क्रमशः बहुगुणा और चंद्रशेखर को दरकिनार कर दिया जो उन्हें कुछ समय से परेशान करते आ रहे थे.

लेकिन यह विजय विनाशकारी भी साबित हो सकती है. बैठक में चंद्रशेखर और बहुगुणा की गैरमौजूदगी ने नई पार्टी के टिकाऊपन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि नई पार्टी के नेतृत्व का मुद्दा खुला छोड़ दिया गया है. वी.पी. सिंह ने टिप्पणी की, "मुझे इस सवाल पर कुछ नहीं कहना." इसके अलावा दूसरी सभी विपक्षी पार्टियों को नई पार्टी में लाने का जटिल सवाल भी अभी अनसुलझा ही है. हालांकि सत्ता के कुछ महत्वाकांक्षी दावेदारों को किनारे पर छोड़ दिया गया है. लेकिन नई पार्टी अभी भी अड़ियल लोगों से भरी हुई है. सबसे बुरी बात यह कि इन लोगों को एक साथ लाने के लिए कोई सर्वमान्य कार्यक्रम नहीं बनाया गया है. पार्टी का अपना कोई वैचारिक आधार भी नहीं है. यह लोकदल के ग्रामीण झुकाव से लेकर कांग्रेस (स) के कुलीन समाजवाद तक के वैचारिक ध्रुवों के बीच हिचकोले खा रही है.

एकता की प्रकिया बेहद यंत्रणा और कुंठाओं से भरी हुई थी. पहली एकता वार्ता 12 जुलाई को बीजू पटनायक के आवास पर बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक के साथ ही शुरू हुई. इस बैठक में जनता पार्टी, लोकदल, जनमोर्चा, कांग्रेस (स), तेलुगु देशम, असम गण परिषद और द्रमुक के नेताओं ने एकता कैसे और किस तरह की होगी, इस पर विचार किया. रामराव और देवीलाल अपने-अपने प्रारूप पहले ही भेज चुके थे. बैठक शुरू होते ही इतनी छोटी-छोटी बातों पर ले-दे होने लगी मानो स्कूली बच्चे झगड़ रहे हों.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मसलन लोकदल ने पटनायक द्वारा बैठक बुलाने पर आपत्ति की क्योंकि देवीलाल को यह बैठक बुलानी थी. लोकदल के लोग तेलुगु देशम के पी. उपेंद्र से भी उलझ पड़े क्योंकि वे देवीलाल की संघीय पार्टी की धारणा के विपरीत रामराव के नेशनल पीपुल्स फ्रंट बनाने के प्रस्ताव पर जोर दे रहे थे. देवीलाल के प्रारूप में संघीय पार्टी के संयोजक के रूप में एक नेता चुनने की बात थी, तो एनटीआर के दस्तावेज में अध्यक्ष और संयोजक दोनों पद रखने का पक्ष लिया गया था. जब विवाद बढ़ा तो वी.पी. सिंह ने सुझाव दिया कि नेतृत्व के मुद्दे को आगे के लिए छोड़कर एकता के तौर-तरीकों पर ही बात की जाए.

महत्वाकांक्षाओं के इस खुले इजहार के कारण ही नहीं बल्कि कई प्रमुख नेताओं की गैरहाजिरी की वजह से भी यह बैठक अधूरी रही. हेगड़े, अजीत सिंह और अरुण नेहरू तो बैठक में थे लेकिन चंद्रशेखर और बहुगुणा नदारद थे. बहरहाल, बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस (स) के विलय से एक मध्यमार्गी दल बनाने की संभावनाएं हैं.

भाजपा के साथ क्या रिश्ता रखें, यह सवाल मध्यमार्गी पार्टियों के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रहा है. इस बार भी यही बात उठी. देवीलाल ने सभी विपक्षी नेताओं को एक गश्ती चिट्ठी में तफसील से लिखा था कि देश के इतिहास में इस नाजुक मोड़ पर विपक्षी एकता क्यों जरूरी है. पर जैसे ही यह चिट्ठी मुख्यमंत्री के हाथ से निकली, इसमें पूर्व समाजवादी और अब जनता पार्टी के नेता मधु लिमये के हाथ से लिखा एक नोट रहस्यमय तरीके से जोड़ा गया (जिस पर उनके दस्तखत नहीं थे) और सब लोगों में बांट दिया गया. इस नोट में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ तीखी बातें लिखी गई थीं. 1978-79 में भी लिमये ने संघ वाला मुद्दा उठाकर जनता सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

नोट पर भाजपा के नेता नाराज हुए और इसकी कैफियत मांगी. हरियाणा में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले देवीलाल इससे मुश्किल में पड़ गए. शुरू में उन्होंने ऐसा नोट भेजने से इनकार किया लेकिन बाद में बताया कि यह नोट उनके पास मधु लिमये ने भेजा था जो असावधानीवश उस चिट्ठी के साथ लग गया.

एकता की कोशिशों में बाधा डालने वाली यह अकेली घटना नहीं थी. पटनायक के घर हुई बैठक में भाग लेने वाले नेताओं ने हालांकि वायदा किया था कि वे वक्त से पहले कोई बात अखबारवालों को नहीं बताएंगे लेकिन छुटभैये नेताओं ने तुरंत कुछ चुने हुए संवाददाताओं को बैठक का विवरण अपनी ओर से मिर्च-मसाले लगाकर देना शुरू कर दिया. जाहिर है कि इसका उलटा असर भी हुआ. मसलन लोकदल महासचिव शरद यादव ने सबसे पहले घोषणा कर दी कि लोकदल, जनमोर्चा और जनता पार्टी का विलय होगा. लेकिन इस घोषणा के समय तक उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी कुछ नहीं बताया गया था. सभी पार्टियों के लोग अपनी पहचान विलीन होने के कारण पहले से ही कुछ उद्विग्न थे. इस घोषणा से वे और परेशान हुए. विपक्षी एकता में अपने लिए अधिक-से-अधिक हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे बड़े नेताओं में भी इस घोषणा से नाराजगी फैली.

और इसके बाद जो खींचतान चली, वह भयंकर थी. कल तक जो नेता वी.पी. सिंह को एकता का मसीहा मान रहे थे, अब वे ही उनसे खौफ खाने लगे. इन्हीं नेताओं ने अखबार-पत्रिकाओं के जरिये वी.पी. सिंह को सांप्रदायिक संगठनों से भी हाथ मिला सकने वाले मौकापरस्त और सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी करने वाले शख्स के रूप में प्रचारित कराना शुरू कर दिया.

खुद जनमोर्चा में भी दरार दिखाई देने लगी. अभी तक की लड़ाई में वी.पी. सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले आरिफ मुहम्मद खां ने पूर्व वित्तमंत्री की आलोचना की. उन्हें आपत्ति इस बात पर थी कि वी.पी. सिंह ने इलाहाबाद में चुनाव प्रचार के लिए उन्हें तो बुलाया नहीं जबकि उनके राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेता सैयद शहाबुद्दीन चुनाव प्रचार करने पहुंच गए.

इस तरह अरुण नेहरू, रामधन और सत्यपाल मलिक जैसे लोगों को भी लगा कि वे दरकिनार कर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री संजय सिंह के नेतृत्व में ठाकुर लोग ही वी.पी. सिंह के करीबी हो गए हैं.

ऐसी ही उठापटक दूसरी पार्टियों में भी चली. मुख्य मुद्दा नेतृत्व की अनसुलझी गुत्थी ही बना. मसलन जनता पार्टी के एक धड़े ने दूसरी पार्टियों के अलग-अलग धड़ों से अपने समीकरण बनाने की कोशिश की. नतीजा यह हुआ कि चारों ओर अस्तव्यस्तता का आलम छा गया.

वी.पी. सिंह को जल्द ही एहसास हो गया कि जब तक वे दूसरे नेताओं के मन में बैठा डर और ईर्ष्या खत्म नहीं करेंगे, बंटाधार हो जाएगा. इसलिए उन्होंने हर नेता से अलग-अलग मिलकर बात करने का फैसला किया. हरेक को भरोसा दिलाया कि नेता बनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है. और नेकनीयती जताने के लिए उन्होंने एक संवाददाता

तरुण चक्रवर्ती

देवीलाल और अजीत सिंह का गठजोड़ हिंदीभाषी क्षेत्र में कांग्रेस की लुटिया डुबो सकता है. तब जाट और दूसरी पिछड़ी जातियां विपक्ष की ओर आएंगी और करीब 125 सीटों का फैसला हो जाएगा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्मेलन करके घोषणा की कि वे सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, "मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं. विपक्ष देश के सामने सामूहिक नेतृत्व का उदाहरण पेश कर सके तो उसे फायदा होगा." पर मामला इतना सरल नहीं था. जनमोर्चा के नेता अब कहने लगे कि वी.पी. सिंह को जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया जाएगा. अरुण नेहरू ने कहा, "वी.पी. सिंह के अलावा किसी और को नेता मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उनकी अपनी साख होने के अलावा लोगों का समर्थन भी उन्हीं के साथ है. दूसरे लोग उन्हें सलाह और दिशानिर्देश दे सकते हैं."

पर वी.पी. सिंह ने किसी भी कीमत पर विपक्षी एकता कराना अपना मुख्य काम माना. एक वक्त तो वे कोई बात बनती न देख रामराव के प्रस्ताव पर भी सहमत हो गए थे जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को नए गठबंधन का अध्यक्ष, वी.पी. सिंह को संयोजक, अजीत सिंह को सह-संयोजक और देवीलाल को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना था. इसके लिए अंतिम तारीख थी 27 जुलाई. लेकिन यह व्यवस्था धरी की धरी रह गई क्योंकि इसमें हेगड़े, चंद्रशेखर, दंडवते और पटनायक के लिए कोई भूमिका नहीं रखी गई थी.

विलय के मामले में एक और बड़ी अड़चन थी. एकाएक इस बात पर ध्यान गया कि नई पार्टी में जाने पर दलबदल कानून के तहत वी.पी. सिंह समेत जनमोर्चा के 11 सांसदों की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी. वी.पी. सिंह इलाहाबाद के मतदाताओं को ऐसा झटका देते तो उनकी छवि ही खराब होती.

बहरहाल, गैर-कम्युनिस्ट विपक्ष ने सीधे गणित भी जोड़ लिया है कि एकता से उसे कितना लाभ होगा. उसका मानना है कि भाजपा और वामपंथियों समेत पूरा विपक्ष अगर एकजुट होकर चुनाव लड़े तो वह कुल 544 में से 350 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकता है. विपक्षी नेताओं का मानना है

लगभग हर चुनाव में कांग्रेस कुल वोटों का अल्पमत पाकर भी गद्दीनशीन होती रही है. यानी सभी विपक्षी दलों को अलग-अलग मिलने वाले वोट एक जगह जुट जाएं तो कांग्रेस को चुनाव में भारी मुश्किल हो सकती है

लोकसभा के लिए पड़े वोटों और जीती गई सीटों का प्रतिशत

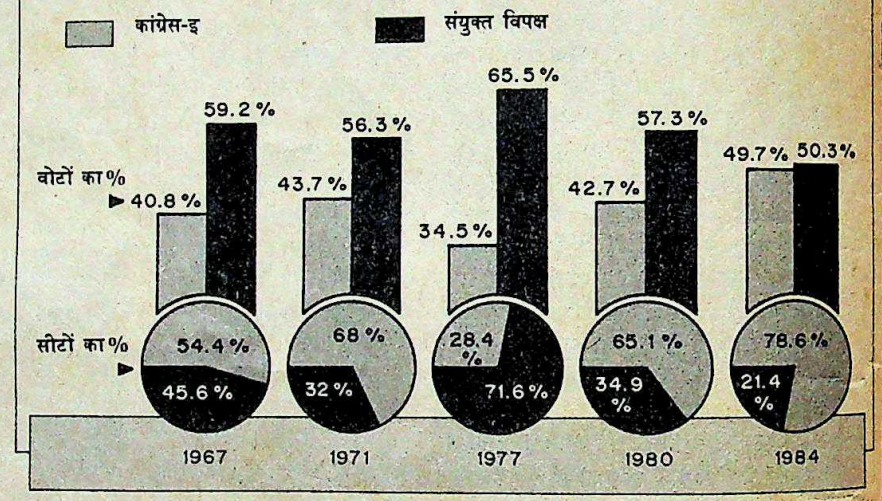

चार्ट: बी.के. शर्मा

विधानसभा के लिए पड़े वोटों और जीती गई सीटों का

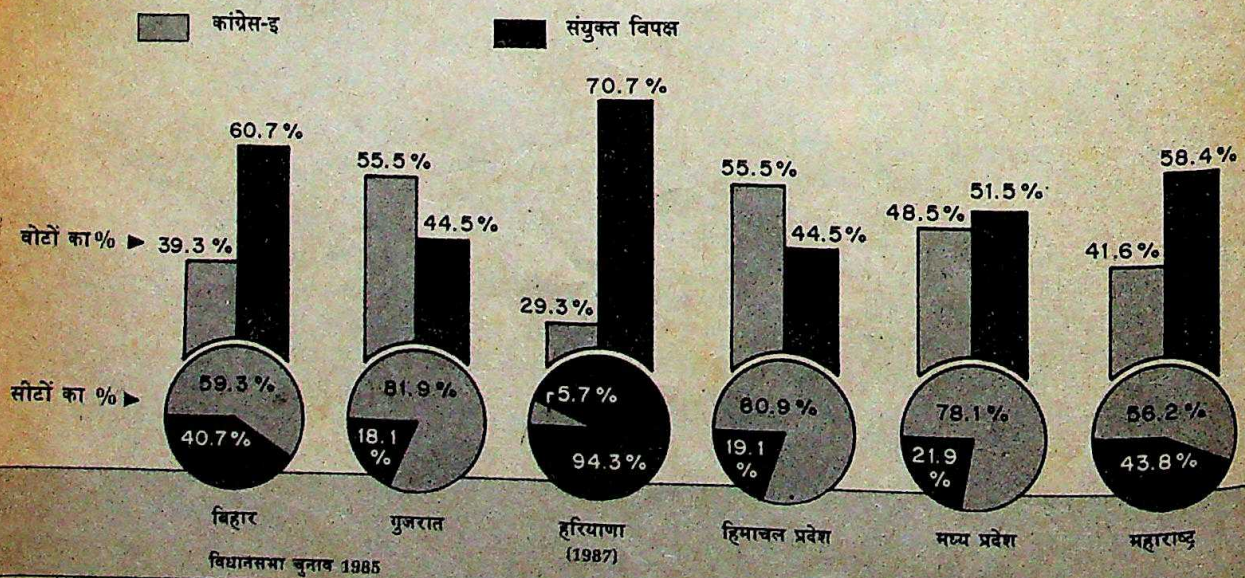

विधानसभा चुनाव 1985

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि असली लड़ाई हिंदीभाषी इलाकों और पश्चिमी प्रदेशों में होगी. इंका दक्षिण से पहले ही उखड़ चुकी है. दिसंबर 1984 में हुए चुनाव में भी उसे दक्षिण की 128 में से 64 सीटों पर ही जीत मिली थी. लेकिन एमजीआर के निधन के बाद अब इंका की सीटें और कम हो जाने की उम्मीद है. अभी तो प्रफुल्ल महंत, रामराव और करुणानिधि जैसे क्षेत्रीय नेता करीब 100 लोकसभा सीटों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं.

पिछले चुनाव में इंका ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और दिल्ली की 222 में से 214 सीटें जीती थीं. पर वी.पी. सिंह अगर देवीलाल और अजीत सिंह के बीच सुलह कराने में कामयाब रहते हैं तो वे हिंदीभाषी क्षेत्र में कांग्रेस की लुटिया डुबाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे. देवीलाल और अजीत सिंह के एक साथ होने से सिर्फ जाट ही नहीं, दूसरी पिछड़ी जातियों के लोग भी विपक्ष की ओर आएंगे और उनके वोटों से ही कम-से-कम 100 सीटों का फैसला हो जाएगा.

विपक्ष को एकजुट होने की प्रेरणा इस बात से भी मिली है कि राजीव की वोट-बटोरू छवि तेजी से खराब होती जा रही है और उधर इंका में भी नाराजगी बढ़ रही है.

लेकिन मौजूदा परिस्थिति में विपक्ष की एकता सचमुच टेढ़ी खीर है. ऐसा सिर्फ नेता के मसले पर विवाद के कारण नहीं बल्कि नई

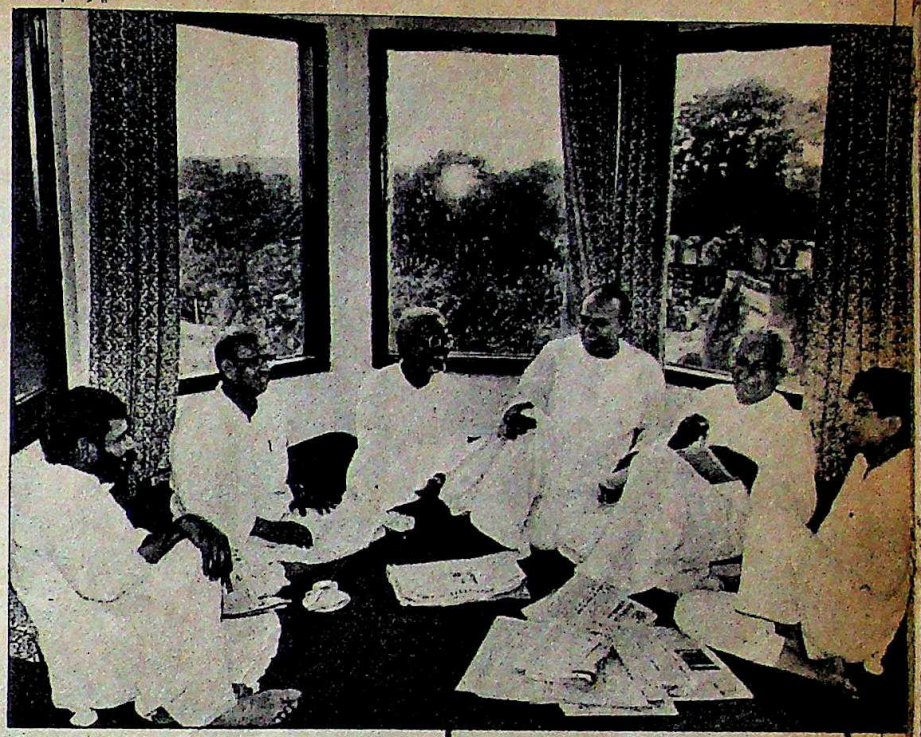

योग जॉय/द ट्रिब्यून

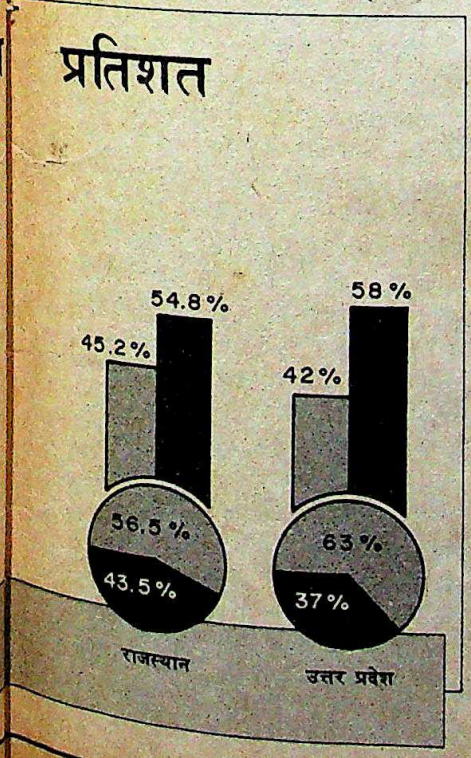

पार्टी में आने वाले सांसदों और विधायकों को दलबदल विरोधी कानून से होने वाली परेशानियों के कारण भी हैं. एकता के मुद्दे पर अभी इतना विवाद है कि इनमें से ज्यादातर लोग इस्तीफा देने से डरते भी हैं. विलय और एकता में इससे भी गंभीर बाधा आ सकती है.

अभी तक विपक्षी एकता एक तरफ समाजवादी जनता दल के गठन और दूसरी तरफ तेलुगु देशम, असम गण परिषद और द्रमुक के साथ उसके संयुक्त मोर्चे के रूप में सामने आई है. विपक्ष की स्पष्ट और ठोस एकता शायद चुनाव पास आने पर ही होगी. बहरहाल इस पखवाड़े दिल्ली में रामराव की अध्यक्षता में होने वाली विपक्षी बातचीत में एकता का मसला और आगे बढ़ेगा. इस बैठक में चुनावी तालमेल, संयुक्त चुनावी प्रचार रणनीति और किन दलों से गठबंधन हो इस पर फैसला होगा. 32 सूत्री कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी.

लेकिन क्या वे चुनाव और उसके बाद तक एक रह पाएंगे? विपक्षी शिविरों में अभी जिस तरह के विवाद हैं, (जिनके सुलझने के आसार नजर नहीं आते) उनसे तो यही लगता है कि यह कुनबा जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा. एकता की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे में ही होगी. हर पार्टी के नेता अपने समर्थकों को टिकट का भरोसा देते जा रहे हैं, ऐसे में टिकट बांटते वक्त जबरदस्त खींचातानी होगी. चूंकि इस बार केंद्र में सत्ता पाने के लिए ही एकता की बात चल रही है इसलिए प्रधानमंत्री पद

जनमोर्चा नेताओं को पूरा भरोसा है कि वी.पी. सिंह के नेतृत्व में ही विपक्षी दलों का ऐसा गठबंधन उभरेगा जिसमें गैर-कम्युनिस्ट पार्टियों के साफ छवि वाले नेताओं की प्रमुख भूमिका होगी

या महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर अपने दावे मजबूत करने के लिए हर नेता अपने अधिक-से-अधिक लोगों को जितवाना चाहेगा.

आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर भी तीखे मतभेद होना तय है. शुरुआती बातचीत में ही लोकदल और जनता पार्टी के लोगों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा करा लेने की कोशिश की. जनता शासनकाल में गठित यह आयोग पिछड़ी जातियों के लिए नौकरी में आरक्षण का सुझाव देने के कारण काफी विवादास्पद हुआ था. अभी यह मुद्दा थोड़ा शांत है लेकिन खतरा बरकरार है कि इससे पूरा विपक्ष कभी भी जातिगत आधार पर बंट सकता है. विदेश नीति के मामलों में बहुगुणा और उनके समर्थक दरअसल कम्युनिस्ट देशों से ज्यादा गहरे रिश्ते बनाने और अधिक आर्थिक नियंत्रण कायम करने पर जोर देंगे. वहीं वी.पी. सिंह और जनमोर्चा के दूसरे नेता एकदम स्वतंत्र विदेश नीति और खुली अर्थ-व्यवस्था का पक्ष लेंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाजपा के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं, "बदकिस्मती से विपक्षी पार्टियां नेता, झंडा और चुनाव चिन्ह जैसे मामूली मसलों पर अटक गई हैं. अगर इन पर सहमति नहीं बनी तो सब कुछ धरा-का-धरा रह जाएगा."

विलय को छोड़कर अभी अनेक बुनियादी मामले तय होने बाकी हैं. सीटों के तालमेल पर बातचीत नाकाम रही है. एक सर्वमान्य नेता के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है. यहां तक कि एक साझा कार्यक्रम भी नहीं बना है. अपनी औकात के बारे में नेताओं की गलतफहमी और उनके क्षुद्र स्वार्थ जनता सरकार के दिनों की याद दिलाते हैं.

पर विपक्ष की मुख्य समस्या विश्वसनीयता का अभाव है. राजीव सरकार की बुराइयां गिनाते वक्त तो विपक्षी नेता इस अंदाज में बोलते हैं मानो वे दूध के धुले ही हों, जबकि ऐसा है नहीं. एकता वार्ता के नाम पर जिस तरह वे क्षुद्र स्वार्थों के लिए चिकचिक मचाए हुए हैं उससे मतदाताओं और देश का कोई बहुत कल्याण नहीं हो रहा. इस सारी जोड़-तोड़ में नम्रता, त्याग और देशसेवा का बुनियादी भाव ही गायब है.

लेकिन इन सारी समस्याओं के बावजूद जनमोर्चा के नेताओं को भरोसा है कि नई पार्टी वी.पी. सिंह के नेतृत्व में आखिर एक ऐसा गठबंधन बनकर उभरेगी जिसमें सभी गैर-कम्युनिस्ट पार्टियों के मध्य स्तर के और साफ छवि वाले नेताओं की प्रमुख भूमिका होगी. उनका दावा है कि ऐसी स्थिति तक पहुंचते ही वी.पी. सिंह को मध्यस्थ की भूमिका सौंपी जाएगी. फिर वी.पी. सिंह राजीव को हटाने के लिए भाजपा और वामपंथियों को भी एकजुट कर लेंगे.

विपक्षी एकता से सत्तारूढ़ दल भी परेशानी महसूस कर रहा होगा लेकिन ऊपरी तौर पर वह इसे मानो हवाई उड़ान मानता है. इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद कहते हैं, "देश पहले भी मौकापरस्त विपक्षी गठबंधन के चलते घाटा सह चुका है. उनके पास महज राजीव गांधी हटाओ जैसा नकारात्मक कार्यक्रम ही है और जितनी पार्टियां हैं, उतने ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं."

यह एक दूसरे की खामियां देखने वाली बात हो सकती है लेकिन आजाद की बात में दम तो है. विपक्ष जब तक किसी उद्देश्य के प्रति दृढ़-निश्चय, लक्ष्य के प्रति गंभीरता, जुनूनी उत्साह और सही बातों के लिए महत्वाकांक्षा नहीं दिखाता, तब तक इन सारी कोशिशों का उलटा ही असर होगा.

—प्रभु चावला और पंकज पचौरी

वामपंथी

साथी चुनने की उलझन

विपक्षी दल भी उनके गुण-दोषों की जांच कर रहे

विपक्ष की 'बुर्जुआ' पार्टियां तो जैसे-तैसे एकता की ओर बढ़ती दिखती हैं पर सर्वहारा का दम भरने वाली वामपंथी पार्टियों की हालत निश्चय ही खराब है. वे उनसे भी ज्यादा उलझन में दिखाई देती हैं.

त्रिपुरा में अपनी हाल की पराजय के बावजूद वे राजनैतिक तौर पर अभी काफी मजबूत हैं. उनकी कुछ नाकामियां ही आज उनकी ताकत बन गई हैं. वे पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा के अपने परंपरागत आधार से बाहर प्रभाव जमाने में नाकाम रही हैं. इसलिए वे अब इस नतीजे पर पहुंची हैं कि दिल्ली की गद्दी में भागीदार बनने के लिए उन्हें दूसरे विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाना ही होगा. लेकिन लाख टके का (नहीं, रूबल) सवाल यह है कि वे किसके साथ गठबंधन करेंगी.

इलाहाबाद उपचुनाव में उन्होंने खुलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया. आज भी अधिकांश वामपंथी लोगों का झुकाव उनकी ही ओर है क्योंकि वे ही राजीव का सबसे ताकतवर विकल्प नजर आते हैं. वाम-

गोर्बाचेव की गुगली

ऊपर लाल वेलवेट के पर्दों से ढकी अलमारी में से लेनिन का संगमरमरी बुत झांक रहा था. सोवियत महावाणिज्य दूत निर्विकार भाव से श्रोताओं को ताकते डेस्क पर झुके हुए बैठे थे. मंच पर मौजूद पश्चिम बंगाल के पांच वाममोर्चा नेताओं में से दो ऊंघ रहे थे. माइक पर प्रदेश भाकपा के मुखिया विश्वनाथ मुकर्जी की आवाज गूंज रही थी, "कोई भी हमें क्रांति का निर्यात नहीं करेगा. कोई भी हमारे लिए क्रांति का आयात नहीं करेगा. क्रांति इस धरती पर अपने-आप पैदा होगी."

चार दशक तक मास्को से विचारधारा की खुराक पाने वाली पार्टी के नेता के मुख से निकले ये शब्द वीरतापूर्ण ही माने जाएंगे. पर कलकत्ता के गोर्की सदन में पिछले पखवाड़े हुए सेमिनार में इस बुजुर्ग भाकपा नेता ने वही कहा जिसे भारतीय वामपंथी गोर्बाचेव के 'ग्लासनोस्त' और 'पेरेस्त्रोइका' का झटका लगने के बाद से ही दुहरा रहे हैं.

मास्को के नए तेवर से भारत के वामपंथी इस कदर चकराए हुए हैं कि उनका सबसे असरदार तबका—माकपा—खुलेआम कुछ कहने तक में सकुचा रहा है. इसीलिए इसके नुमाइंदे सेमिनार से दूर ही रहे. पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्तमंत्री अशोक मित्र स्वीकार करते हैं, "कई तरह के भ्रम हैं. कम्युनिस्टों का सवाल है कि आखिरकार हम किसका परचम उठाए फिर रहे हैं. जहां क्रांतिकारी ताकतों का सरपरस्त परिवर्तनों के ऐसे व्यापक दौर से गुजर रहा हो वहां भारत के साम्यवादियों पर असर पड़े बिना कैसे रह सकता है?"

इस बदलाव का उन पर जो असर पड़ा है उसे छुपाना आसान नहीं है. भारतीय कम्युनिस्ट वामपंथी जगत में सबसे कट्टर परंपरावादी माने जाते हैं. उनके लिए स्टालिन को तलाक देकर ट्राटस्की की शरण में चले जाने जैसे वैचारिक बदलाव वाले गोर्बाचेव के सुझाव अधर्म की तरह हैं. माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और इसकी बंगाल शाखा के महासचिव सरोज मुकर्जी कहते हैं, "हम स्टालिन के रहते पैदा हुए और बढ़े हैं. हम उनका बहुत सम्मान करते हैं." गोर्बाचेव के बदलावों के खिलाफ मार्क्सवादी अभियान के सूत्रधार, पोलित ब्यूरो के सदस्य बी.टी. रणदिवे जोड़ते हैं, "कथित रूसी बुद्धिजीवी, उनके शोधकर्ता और वैज्ञानिक स्टालिन को ऐसे त्याग रहे हैं जैसे उनके समय में कोई अच्छी बात हुई ही नहीं. जैसे वे सिर्फ शैतान थे. फिर ट्राटस्की को किसने पराजित किया? नाजियों को किसने हराया? यह इतिहास की ही अनदेखी है. वे खुद अपने समाजवाद को बदनाम कर रहे हैं." केरल के मुख्यमंत्री ई.के. नयनार कहते हैं, "पूरे 70 साल समाजवादी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मोर्चा के प्रमुख चिंतक और पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्तमंत्री अशोक मित्र कहते हैं, "हमारे लिए राजीव मध्यकालीन युग के प्रतिनिधि हैं. उनके किसी भी विरोधी से गठबंधन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है."

लेकिन चुनावी रणनीति के तहत गठबंधन करने के लिए भी वामपंथी किस हद तक वैचारिक 'समझौता' करेंगे; यह सवाल महत्वपूर्ण है. विशुद्ध मार्क्सवादी चश्मा लगाते ही उन्हें सारी राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियां प्रतिक्रियावादी नजर आने लगती हैं. लेकिन इंका को हराने के लिए इन्हीं दलों से गठबंधन करना उनकी मजबूरी है.

वामपंथी चिंतक थोड़ी झिझक के साथ स्वीकार करते हैं कि जिन दलों को वे 'विपक्षी' मानकर एक खेमे में डाल देते हैं उनमें से कई इंका से भी ज्यादा दक्षिणपंथी हैं. माकपा पोलितब्यूरो के सदस्य और उसकी पश्चिम बंगाल राज्य शाखा के महासचिव सरोज मुकर्जी इस विरोधाभास की व्याख्या देते हैं, "हमारे दो तरह के उद्देश्य हैं. तात्कालिक उद्देश्य तो इंका को हटाना है और अंतिम उद्देश्य समाजवाद कायम करना. लेकिन आज देश की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस को हटाना बाकी सभी मुद्दों से ऊपर हो गया है." वामपंथी आंदोलन के दूसरे घटक भी इस मामले में ऐसी ही राय रखते हैं.

पर उनके नेता इस सवाल पर एकमत नहीं कि पहला उद्देश्य कैसे हासिल किया जाए. वे ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते जिसमें भाजपा सरीखी सांप्रदायिक पार्टियां शामिल हों. यही वामपंथियों की दुविधा है. पहले वे अकाली दल और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में रहे हैं और इनमें से कोई पार्टी भाजपा से कम सांप्रदायिक नहीं मानी जा सकती.

लेकिन अच्छा कम्युनिस्ट वही है जो हर चीज की 'द्वंद्वात्मक' व्याख्या कर दे. इसलिए अकाली दल और लीग से गठबंधन को यह कहकर सही ठहराया गया कि ये छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं तथा इनसे राष्ट्रीय स्तर पर कोई खतरा नहीं है. कलकत्ता की रैली को बहुत प्रचारित नहीं किया गया. वाममोर्चा के एक समर्थक का कहना है, "भाजपा नेताओं के साथ एक ही मंच से

कार्टून: अजीत नैनन

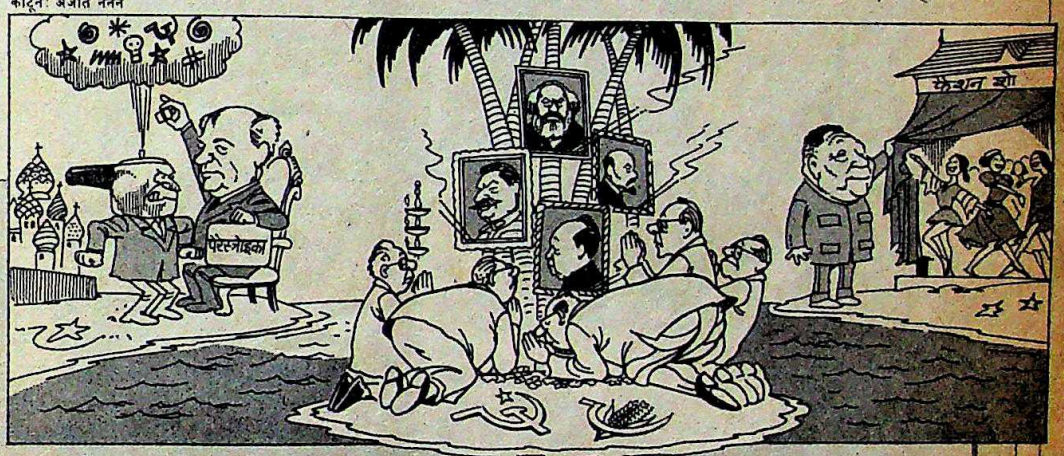

सोवियत संघ और चीन में बदलाव की खबरें आने के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट खासकर माकपा अपनी पुरानी वैचारिक लाइन छोड़ने को तैयार नहीं हैं

तौर-तरीकों से बिताने के बाद रूस में इस पर थोड़ा-बहुत विचार हो रहा है. पर गोर्बाचेव जो कह रहे हैं भारत के साम्यवादी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते."

पर माकपा के कट्टर समर्थक भी मानते हैं कि आज के कम्युनिस्ट स्तालिन के दमनकारी तौर-तरीके नहीं अपना सकते. कलकत्ता में मार्क्सवादी विचारधारा की नर्सरी, प्रेसीडेंसी कॉलेज में दो दशकों तक अध्यापन कर चुके प्रशांत राय कहते हैं, "स्टालिन जैसी अनुकूल स्थितियों में आज कोई नहीं है. लोहे या बांसों की दीवार के पीछे समाजवाद की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती. आज तो लोगों को नई अर्थव्यवस्था की सचाइयों के मुताबिक ही चलना होगा."

भारत के कम्युनिस्ट इस बात से और भी चकरा गए हैं कि रूस में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव के कारण पेइचिंग में भी उदारवाद की हवाएं चलने लगी हैं. कलकत्ता के मशहूर वकील और पश्चिम बंगाल के पूर्व महाधिवक्ता अरुण प्रकाश चटर्जी कहते हैं, "मार्क्सवाद किसी की बपौती नहीं है. यह एक विज्ञान है." मुकर्जी जोड़ते हैं, "हम उनका अंध समर्थन क्यों करें? हमारा साम्यवाद देंग और गोर्बाचेव के साम्यवाद से कहीं बेहतर और शुद्ध है."

बेहतर हो या न हो लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय साम्यवादी यह झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं. मास्को द्वारा भारतीय वामपंथियों की बढ़ती आलोचना के मद्देनजर यह झटका उनके लिए कुछ ज्यादा ही जोरदार रहा है. माकपा के लिए तो मास्को के नए तेवर खासतौर पर निराशाजनक हैं मास्को का रूख ऐसे समय पलटा जब पार्टी, संगठन में सिर उठाती 'नुकसानदेह और अधोगामी' प्रवृत्तियों से निपटने के लिए ज्यादा कट्टर रवैया अपनाने पर गौर कर रही है.

पार्टी नेताओं के लिए गोर्बाचेव एक नई, अजनबी पीढ़ी के नुमाइंदे हैं. माकपा के ज्यादातर बड़े नेताओं का सैद्धांतिक प्रशिक्षण स्टालिन के जमाने में हुआ. इसका जीता-जागता सबूत है पोलितब्यूरो के सदस्यों की औसत आयु जो 74.2 साल है. उनके लिए इतना बड़ा बदलाव पचा पाना खासा मुश्किल है.

मास्को में हो रहे सैद्धांतिक परिवर्तनों का असर भारत में वाममोर्चे की राजनीति पर भी पड़ रहा है. वाममोर्चा के बाकी सभी घटकों— भाकपा, विप्लवी समाजवादी दल (आरएसपी) और फारवर्ड ब्लॉक ने परिवर्तनों का स्वागत किया है. इससे उनमें और प्रमुख घटक माकपा में सैद्धांतिक खाई बन गई है. आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक तो अभी भी हाशिए पर हैं लेकिन तय है कि भाकपा और माकपा के एकता प्रयास उलटी दिशा में चल पड़ेंगे.

भाकपा पर दबाव पड़ने लगा है कि वह राजीव गांधी का साथ देने की नीति पर चलने के लिए सैद्धांतिक रूप से मास्को पर ही आश्रित रहे. और चूंकि माकपा के साथ उनके सैद्धांतिक मतभेदों की खाई चौड़ी होती जा रही है ऐसे में तय है कि यह नुस्खा फूट और वैमनस्य को ही जन्म देगा.

—शेखर गुप्ता, कमलजीत रतन और श्रीधर पिल्लै के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

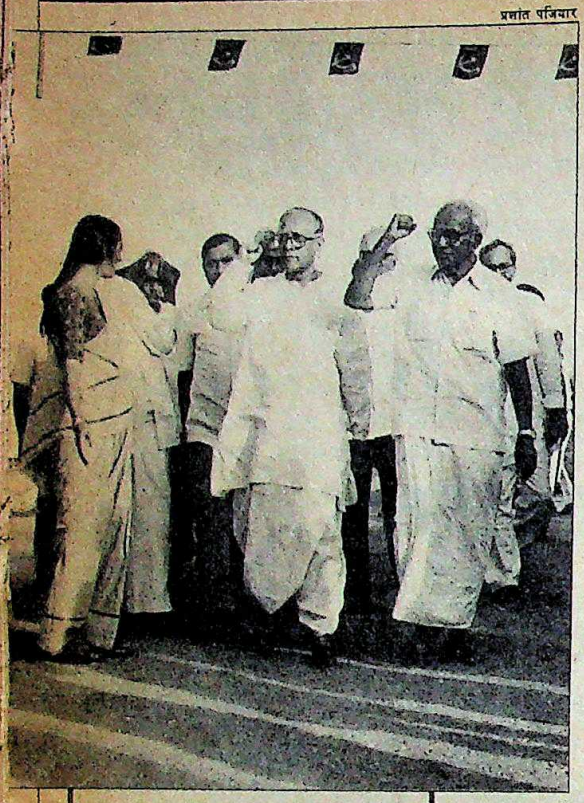
प्रशांत पंजियार

ज्योति बसु (बीच में) और नबूंदिरिपाद: दृढ़ निश्चय

सारी समस्याओं और कमजोरियों के बावजूद सचाई यह है कि इंका और वी.पी. सिंह के बाद वामपंथी ही देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनैतिक ताकत हैं

ज्योति बसु का बोलना एकदम अलग मामला है. उन्हें वहां भाषण देने के लिए बुलाया गया था और वे आयोजकों से यह नहीं कह सकते थे कि अटलबिहारी वाजपेयी को मंच से उतार दें."

एक ओर तो वामपंथी अपने 'भरोसेमंद' साथी खोजने को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरे विपक्षी दल भी उनके गुण-दोष की जांच-पड़ताल कर रहे हैं. विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि जब भी मुश्किल घड़ी आएगी, कम्युनिस्ट इंका के साथ हो लेंगे. इस मुहिम की अगुआई भाजपा कर रही है. भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी पूछते हैं, "उनके रिकार्ड को देखते हुए हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?"

कम्युनिस्टों के आलोचक बताते हैं कि उन मौकों पर, जब इंका को उखाड़ फेंका जा सकता था, वामपंथियों ने ही उसे सहारा दिया. यह क्रम 1969 में श्रीमती गांधी का साथ देने से शुरू हुआ. वामपंथियों ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती गांधी के उम्मीदवार वी.वी. गिरि को समर्थन दिया. 1987 में भी उन्होंने वेंकटरामन के खिलाफ जैल सिंह को बागी उम्मीदवार बनाने की हिमायत नहीं की. वामपंथी भी मानते हैं कि उनसे गलतियां जरूर हुई हैं लेकिन जैल सिंह को उम्मीदवार न बनाना सही था. माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य बी.टी. रणदिवे ने 'इंडिया टुडे' को बताया, "हम आम जनता के सहयोग से राजीव गांधी को तो हटाना चाहते हैं. पर हम ऐसा उन (जैल सिंह) जैसे लोगों की मदद से नहीं करेंगे जो अकाल तख्त के सामने दंडवत हो जाते हैं."

लेकिन खुद वामपंथियों पर अपने मास्को या पेइचिंग के 'आकाओं' के सामने दंडवत होने का आरोप लगाया जाता है. हाल ही में राजीव गांधी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था. वामपंथी हालांकि इसका खंडन करते हैं पर इस बात में शक नहीं कि अभी तक वामपंथियों के अनेक धड़े 'क्रांतिकारी' महाशक्तियों से निर्देश लिया करते और उन पर चलते थे.

इसी संदर्भ में सोवियत संघ द्वारा राजीव सरकार का जबरदस्त समर्थन वामपंथियों और बाकी विपक्ष को चिंतित किए हुए है. हाल ही में सोवियत संघ ने कई बार भारतीय कम्युनिस्टों को इंका का विरोध करने पर 'प्रतिक्रियावादी' करार दिया है.

कम्युनिस्टों के लिए यह बहुत अपमानजनक बात है. सरोज मुकर्जी कहते हैं. "अफसोस है कि वे भारतीय कम्युनिस्टों को प्रतिक्रियावादी कहते हैं." लेकिन सोवियत संघ के इस अभियान का मकसद एकदम स्पष्ट है. वह धौंस दिखाकर भारतीय कम्युनिस्टों से इंका का समर्थन कराना चाहता है, और इस बात का अंदेशा विपक्ष के दक्षिणपंथी तत्व हमेशा जाहिर करते आए हैं. लेकिन माकपा महासचिव ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद ने पिछले पखवाड़े इन अंदेशों को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा, "संन्यासी अगर संन्यासी ही बनकर चुपचाप रहें तब तो उनका आदर करेंगे. लेकिन अगर वे राजनीति में दखलंदाजी करें तो हम दूसरे राजनीतिकों की तरह उनका भी मुकाबला करेंगे." दूसरे वामपंथी दलों ने अभी सोवियत संघ की मौजूदा लाइन पर ऐसी खुली टिप्पणी नहीं की है.

और इस कारण संदेह और बढ़ा है, खासकर भाकपा को लेकर, जो दो दशकों से मास्को की लाइन पर चलती आ रही है. भाकपा ने बड़े ही दास भाव से गोर्बाचेव के मौजूदा सुधारों का समर्थन किया है. पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में रहने वाले उसके 69 वर्षीय सचिव, एम. फारूकी कहते हैं, "महासचिव गोर्बाचेव के सुधार मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर लाया जाने वाला समाजवाद है."

साथ ही भाकपा का कहना है कि भारतीय राजनीति में वह मास्को से स्वतंत्र होकर अपनी दिशा तय करेगी. इस कारण स्थिति दुविधापूर्ण हो गई है. पार्टी का बुढ़ाता नेतृत्व अभी तक सोवियत संघ से इतना जुड़ा रहा है कि वह एक बार में उससे पूरी तरह अलग नहीं हो सकता. जब भी नाजुक मौका आएगा, उन पर राजीव का समर्थन करने के लिए मास्को से भारी दबाव पड़ सकता है. इसके अलावा भाकपा का एक समूह शुरू से ही कांग्रेस और नेहरू परिवार के प्रति बहुत लगाव रखता है.

बहरहाल, इन सारी समस्याओं और अंदरूनी कमजोरियों के बावजूद सचाई यह है कि इंका और वी.पी. सिंह के बाद वामपंथी ही देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनैतिक ताकत हैं. विपक्षी नेता भी इस बात को मानते हैं. जनता पार्टी के अध्यक्ष अजीत सिंह कहते हैं, "तीन राज्यों में वामपंथियों का प्रभुत्व है. देश भर में उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं." दूसरी ओर इंका ने इस मामले पर जानबूझकर चुप्पी साध रखी है. उसकी रणनीति यही है कि वामपंथियों पर मास्को से दबाव डलवाया जाए.

लेकिन इस तरकीब के काम न देने पर इंका चुनाव के समय समाजवादी आर्थिक कदम उठाने का अपना तुरूप का पत्ता फेंककर वामपंथियों को लुभाने की कोशिश कर सकती है. अगर ऐसा करके शासक दल वामपंथियों के एक धड़े का भी समर्थन हासिल कर लेता है तो यह विपक्षी रणनीति के लिए बहुत बुरा साबित होगा.

—शेखर गुप्ता, फरजंद अहमद, एन नैनन और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

नाजुक मोड़ पर नुकसान

नरमपंथी नेताओं की हत्या से अमन की कोशिशों को झटका

लुधियाना में गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास दो हत्यारों द्वारा दागी गई तीन बुलेटों ने जो नुकसान किया है वह पिछले पखवाड़े एके-47 द्वारा दागी गई दर्जनों गोलियों ने नहीं किया.

जिन तीन व्यक्तियों को गोली मारी गई वे ऐसे शख्स थे जिन्हें पंजाब के इस नाजुक मोड़ पर सरकार कतई खोना नहीं चाहती थी. स्वर्णमंदिर के मुख्यग्रंथी ज्ञानी सोहन सिंह, शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के कार्यालय सचिव भान सिंह और महासचिव माल सिंह घुम्मन राज्य में शांति कायम करने की कोशिशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे. माना जाता है कि ये तीनों नेता नरमपंथी अकाली गुटों को एकजुट करने की कोशिशों में लगे थे. शायद इसी वजह से ही वे आतंकवादियों का निशाना बन गए.

पंजाब पुलिस मानती है कि इन तीनों के नाम पिछले दो महीने से हिटलिस्ट में थे. इन लोगों ने ही जसबीर सिंह रोडे और उनके चार समर्थकों को मुख्यग्रंथियों के पदों से हटवाने में अहम भूमिका अदा की थी. इस वजह से ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएसएफ) और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) जैसे कुछ उग्रपंथी गुटों में उनके प्रति भारी नाराजगी थी. केएलएफ के मुखिया अवतार सिंह ब्रह्मा ने घुम्मन और भान सिंह को धमकी भी दी थी. हालांकि सोहन सिंह विवादास्पद ग्रंथी नहीं थे लेकिन पिछले महीने उन्होंने सुरजीत सिंह बरनाला को पंथ में शामिल कराने की पहल की थी. इस कारण आतंकवादी उनसे भी नाराज थे.

ये सारी बातें जगजाहिर थीं. फिर भी सरकार उनकी रक्षा करने में विफल रही. पुलिस की दलील है कि उसका कोई दोष नहीं. तीनों नेताओं को हथियारबंद सुरक्षा गार्ड दिए गए थे. लेकिन उस अभागी दोपहर को जब वे इंजीनियरिंग कॉलेज गए तो उन्होंने खुद सुरक्षा गार्डों से अपने हथियार साथ न रखने को कहा था. उनका ख्याल था कि हथियार देखकर छात्र भड़क सकते हैं.

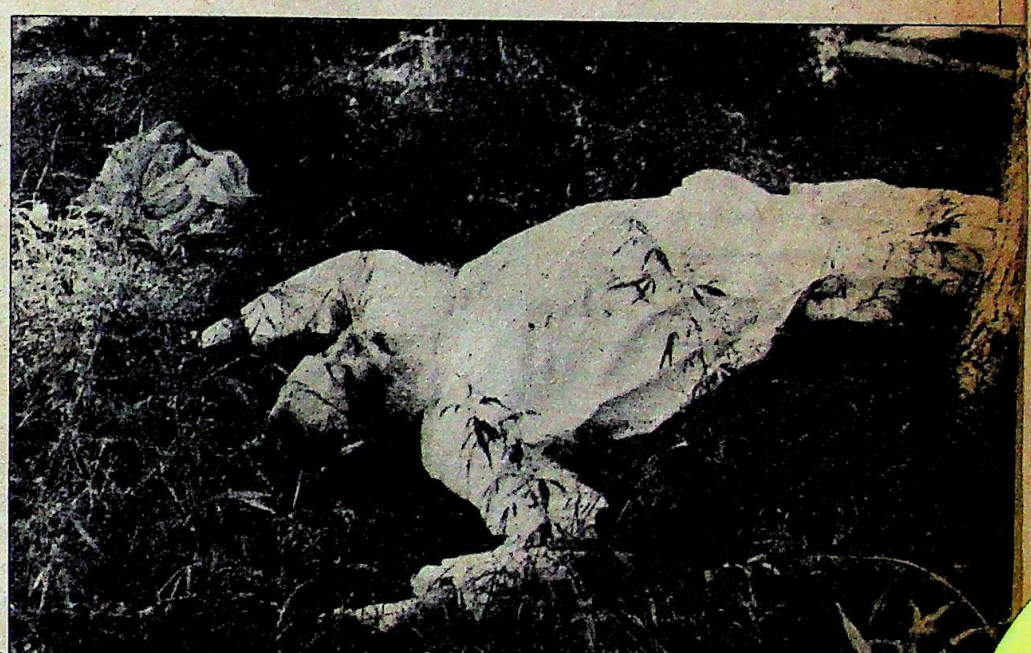

मुख्यग्रंथी सोहन सिंह का शव: जघन्य हत्या

उग्रवादियों के खेमे में तीनों नेताओं ने कितनी हलचल मचा दी थी, इसका पूरा अंदाज उन्हें नहीं था. एकीकृत अकाली दल के गिरफ्तार नेता प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह तोहड़ा, जगदेव सिंह तलवंडी और भिंडरांवाले के पिता बाबा जोगिंदर सिंह सरीखे गरमपंथी नेताओं के लिए विकट चुनौती एकता की कोशिशें ही रही हैं.

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती घुम्मन का कहना था, "ज्ञानी सोहन सिंह तो पंथिक एकता के जरिये एसजीपीसी और कई गुटों में बंटी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे. अब साफ जाहिर हो गया है कि आतंकवादी पंथ को कमजोर कर रहे हैं." घुम्मन स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नजदीकी सहयोगी रहे हैं. वे इस हादसे से कतई विचलित नहीं हैं, "कृपया लोगों तक मेरा यह संदेश पहुंचा दें कि आतंकवाद से कोई मसला हल नहीं हो सकता."

अकाल तखत के पूर्व जत्थेदार दर्शन सिंह रागी को इस बात से सदमा पहुंचा है कि आतंकवादियों ने 'सोहन सिंह सरीखे सूफी संत' की हत्या कर दी. रागी का कहना था, "जो लोग ज्ञानी सोहन सिंह और भान सिंह सरीखे सच्चे सिखों की हत्या कर रहे हैं वे न तो धरम की कोई मदद कर रहे हैं और न ही इस देश की."

दरअसल, ये हत्याएं नरमपंथी अकालियों को एक सख्त चेतावनी है. वैसे इससे उग्रपंथियों की आपसी गुटबाजी भी उजागर हुई है. अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि हथियारबंद और भूमिगत युवकों का एक गुट अभी भी रोडे समर्थक है. बहरहाल, इन हत्याओं से नई दिल्ली के कुछ लोगों को भी सदमा लगा. अभी तक रोडे का समर्थन कर रहे कुछ सरकारी नुमाइंदो को अब नई नीति बनानी होगी.

इस वारदात से कुल मिलाकर यही चेतावनी फिर मुखर रूप से सामने आती है— 'खालिस्तान' के लिए अपने पागलपन की रौ में आतंकवादी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, अपने सबसे पवित्र धार्मिक स्थल को अपवित्र करने से लेकर बेकसूर और सम्मानित ग्रंथियों की जघन्य हत्या करने तक.

—विपुल मुद्गल, लुधियाना में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नेहरू खानदान

अपनों पर पराया हमला

बिफरे अरुण नेहरू, रवि टिक्कू ने दिया करारा जवाब

इंका के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी का जुबान संभालकर बोलने से जरा दूर का ही रिश्ता है. अपने नेता राजीव गांधी को खुश करने के लिए वे उनके दुश्मनों के खिलाफ नमक मिर्च लगाकर ऊलजुलूल कहने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन पिछले पखवाड़े उनके मुखारविंद से जो कुछ निकला उससे स्पष्ट हो गया कि बिहार का नाटे कद का यह नेता पार्टी के भले के लिए ही सही, जरूरत से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है.

उनका निशाना थे प्रधानमंत्री के भाई अरुण नेहरू. लेकिन इस मामले में केसरी की कड़वी जुबान ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया. उन पर मानहानि का मुकदमा ठोंकने की धमकी दी गई. अपने निंदा अभियान में केसरी ने कश्मीर के नेहरुओं के खिलाफ भी भद्दी टिप्पणियां की थीं. पूरे देश में राजीव के कश्मीरी संबंधियों ने इसका कड़ा विरोध किया और धमकी दी कि वे राजीव को अच्छे एका वाले, प्रभावशाली विशिष्ट कश्मीरी ब्राह्मण वर्ग से अलग कर देंगे.

वैसे तो बुजुर्ग इंका नेता अपने विरोधियों की कड़ी आलोचना करने के अभ्यस्त हैं लेकिन इस बार उनमें से कई निजी बातचीत में कहते हैं कि केसरी ने गलत जगह वार कर दिया है, हालांकि उन्होंने ऐसा आलाकमान के आशीर्वाद से किया. केसरी ने राजनैतिक स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर हमला किया. उन्होंने अरुण नेहरू की बेटी राधिका की सगाई जैसे नाजुक मौके पर नेहरुओं पर कीचड़ उछाला. राधिका की सगाई जून में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग की हस्ती रवि टिक्कू के बेटे विक्रम टिक्कू से हुई.

पिछले महीने केसरी ने अपने दफ्तर में प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई और दो पृष्ठों का एक बयान जारी किया. इसमें लिखा था, "अरुण नेहरू ने हाल ही में जहाजरानी की हस्ती रवि टिक्कू से जो रिश्ता किया है, उसके बारे में वे राष्ट्र को सफाई दें. रवि टिक्कू 1980-81 में दिवालिया थे लेकिन आज वे 60 करोड़ डॉलर का एक जहाज बनाने की स्थिति में हैं." यह संकेत करते हुए कि नेहरू के राजनैतिक प्रभाव के कारण टिक्कू संपन्न हुए हैं, केसरी ने मांग की, "लोग जानना चाहेंगे कि क्या नेहरू इस तरह के रिश्ते के जरिये अपने गुप्त विदेशी खातों को नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं."

केसरी यहीं नहीं रुके. उन्होंने वंशावली की पंडिताई भी बघार दी, "मुझे विश्वास है कि भारत के लोग मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बेटी इंदिरा जी और उनके दो बेटों—संजय और राजीव जी के अलावा किसी नेहरू को नहीं जानते." जल्दी ही दूसरे इंकाई नेता भी केसरी की आवाज में आवाज मिलाने लगे. दो हफ्ते बाद इंका महासचिव केदारनाथ सिंह ने व्यंग्य कसा, "कुछ ऐसे भी नेहरू थे जो तांगा और रिक्शा खींचते थे."

नेहरू वंश के निजी मामले के रूप में जो बात शुरू हुई, वह देश की सबसे चर्चित घटना बन गई. चूंकि अरुण नेहरू के परिवार में यह पहली शादी हो रही है, लिहाजा उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को न्यौतने का फैसला किया. नेहरू की पत्नी सुभद्रा ने राजीव को एक निजी चिट्ठी लिखकर उनसे और सोनिया से सगाई समारोह में आने और वर-वधू को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया. सगाई समारोह में बी.के. नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित के नजदीकी संबंधी और पद्मा सेठ भी थीं. मेनका गांधी, अरुण सिंह और अजीत हक्सर भी मौजूद थे. लेकिन राजीव और सोनिया नहीं पहुंचे.

इस पर कश्मीरी क्षुब्ध हो उठे. परिवार के एक प्रमुख सदस्य ने रोष से कहा, "जो एक शानदार पारिवारिक समारोह होना चाहिए था, राजीव ने उसका भी राजनीतिकरण कर दिया." लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि राजीव और सोनिया को कोई न्यौता नहीं मिला. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राजीव ने राधिका को उसकी सगाई पर बधाई संदेश भेजा. लेकिन यह बधाई संदेश भी नेहरू के अकबर मार्ग निवास पर ठीक उसी दिन पहुंचा, जिस दिन केसरी ने राधिका के पिता और उसके होने वाले ससुर के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की घोषणा करने के लिए प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई थी.

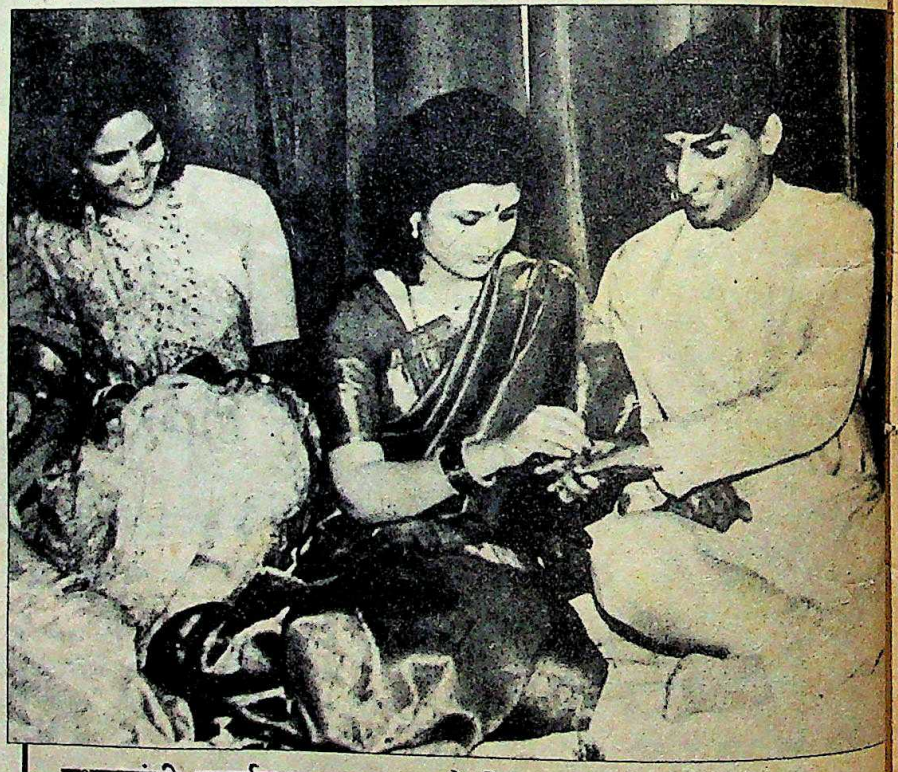

प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि राजीव ने राधिका को उसकी सगाई पर बधाई संदेश भेजा

कोई भी यह नहीं मान सकता कि ऊपरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समर्थन और प्रोत्साहन के बिना इंका के पदाधिकारी अरुण नेहरू पर ऐसा हमला करने का साहस कर सकते थे. इसके बाद तो नेहरू और टिक्कू बाघ की तरह झपट पड़े. टिक्कू ने केसरी पर मानहानि मुकदमा ठोक दिया है. एक करोड़ रु. का हर्जाना दावा किया गया है. केसरी फिर ऐसे बयान देंगे तो दावा 5 करोड़ का किया जाएगा. टिक्कू ने कहा, "दुनिया जानती है कि 1980-81 में मेरे पास टैंकर थे. ये टैंकर दुनिया में सबसे बड़े थे. मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे खिलाफ लगाया गया दिवालिएपन का आरोप केसरी की कल्पना की उपज है."

17 पृष्ठों वाली कानूनी नोटिस में केसरी से खास तौर पर कहा गया कि "आपने प्रेस को जो बयान दिया है, उसे वापस लें, अपनी गलती मानें और बिना शर्त माफीनामा दें और उसे प्रकाशित करें." टिक्कू ने कहा, "केसरी और नेहरू अपनी राजनैतिक दुश्मनी खुद सुलटाएं लेकिन हम अपने पर हुए व्यक्तिगत हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे."

टिक्कू ने अपने पर मढ़े गए आरोपों का असर दूर करने के लिए भारत के वरिष्ठ जनसंपर्क सलाहकारों और पत्रकारों की भी सेवाएं लीं. इस अरबपति की लंबी-चौड़ी व्यावसायिक उपलब्धियों का ब्यौरा प्रभावशाली लोगों के बीच बांटा जा रहा है. टिक्कू के करीबी सूत्रों को संदेह है कि भारत के उद्योगों में पूंजीनिवेश करने के टिक्कू के विचार की वजह से प्रतिद्वंद्वी व्यावसायिक समूह उनके खिलाफ बदनामी का अभियान चला रहे हैं.

उधर नेहरू भी केसरी के खिलाफ आपराधिक मामला दायर करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने 14 जुलाई को केसरी को दो पृष्ठों की एक चिट्ठी भेजी. उसमें उन्होंने लिखा, "मेरे खिलाफ बयान जारी करके आपने दूसरों का प्रवक्ता होने की भूमिका ही निभाई है. आपके असंयमित बरताव से मुझे यकीन हो गया है कि आपने अपनी पार्टी के सर्वोच्च पदाधिकारी के निर्देश पर बयान जारी किया है." निश्चित ही नेहरू बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं.

केसरी ने उनके ऊपर गुप्त विदेशी खाते रखने का आरोप लगाया था. लिहाजा उन्होंने केसरी और सरकार को अपना पावर ऑफ अटार्नी देने की पेशकश की और उन्हें चुनौती दी कि वे इन खातों को खोज निकालें. उन्होंने केसरी को लिखा, "आप इस चिट्ठी को अधिकारपत्र के रूप में मान सकते हैं जोकि आपके या आपको निर्देश देने वाले के नाम जारी किया गया है. मेरी कामना है कि वे लोग भी आपको ऐसा ही अधिकार दें जिनके गुप्त विदेशी खाते हैं."

एक तरफ जहां नेहरू की यह चुनौती राजनीति से प्रेरित थी, वहीं दूसरे कश्मीरियों ने भी केसरी के बयान का विरोध किया. विजयलक्ष्मी पंडित ने सख्त चिट्ठी लिखकर राजीव से अनुरोध किया कि वे अपने राजनैतिक सहयोगियों को नेहरू वंश पर कीचड़ उछालने से रोकें. नेहरू वंश के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, "अपने बेइमान पार्टी कार्यकर्ताओं को इस तरह की छूट देकर राजीव खुद को कश्मीरियों से क्यों अलग कर रहे हैं? हम यह कभी पसंद नहीं करेंगे कि कोई सार्वजनिक रूप से हमें बदनाम करे."

लेकिन केसरी ने नेहरू और टिक्कू के बयान जारी करने के तुरंत बाद पिछले पखवाड़े एक दूसरी प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई और कहा, "मैंने नेहरू के बारे में जो कुछ कहा है, उस पर कायम हूं. नेहरू ने कांग्रेस की संस्कृति कभी नहीं सीखी. वे सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, चाहे वह कंपनी के लिए हो जिसके लिए उन्होंने कभी काम किया, या फिर अपने लिए."

इस विचित्र मामले की विडंबना यह है सार्वजनिक रूप से उछाले जा रहे कीचड़ से, जिसका मकसद नेहरू खानदान को सिर्फ राजीव से जोड़ना है, सिर्फ नेहरू नाम ही बदनाम हो सकता है और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है. —प्रभु चावला

(दाएं ऊपर से) केसरी; टिक्कू के साथ नेहरू; और (बाएं) वर-वधू

बहुत से बुजुर्ग इंकाइयों का मानना है कि केसरी अरुण नेहरू और उनके परिवार पर हमला करने में हदें लांघ गए हैं, हालांकि ऐसा उन्होंने आलाकमान के आशीर्वाद से किया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली

लापरवाही का कहर

अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और थोथी बहानेबाजी से लोग खफा

एक ओर मृत्यु अपना तांडव दिखा रही थी, दूर री ओर एक बेहूदा नाटक खेला जा रहा था. पिछले महीने पूर्वी दिल्ली में हैजे और आंत्रशोथ के भयंकर प्रकोप से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे और जिनकी लापरवाही से यह कहर टूटा था, वे अफसर अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर मढ़ने की तिकड़मों में लगे हुए थे.

सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही 15,000 मरीजों का इलाज हुआ. पिछले पखवाड़े मौतों का आंकड़ा 200 तक पहुंच रहा था. इनमें से आधी संख्या साल भर से भी कम उम्र के बच्चों की थी. उत्तरी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के छोटे शहरों से भी मौतों की खबर मिली. लेकिन दिल्ली में सरकारी लापरवाही के चलते महामारी कलंक बन गई. इसकी फौरी वजह थी शहर के कई भागों में इस्तेमाल किया जाने वाला हैंडपंपों का पानी. पिछले महीने के शुरू में हुई भारी बारिश से नालियां उफन पड़ीं और सार्वजनिक शौचालयों का मल-मूत्र हैंडपंप से आने वाले पानी में मिल गया.

इन इलाकों में मक्खियां और मच्छर गलियों और यहां तक कि दरवाजों तक फैली हुई गंदगी के ढेर पर आराम से मंडराते रहते हैं. दस्त से लस्त हुए दो-दो, तीन-तीन बच्चे एक ही खाट पर पड़े दिखते हैं. भयंकर उमस और असहनीय बदबू अब उन पर बेअसर है. नंद नगरी की 35 वर्षीया कांता देवी ने कहा, "हर घर में बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं. कुछ को दस्त लगे हैं, कुछ को फुंसियां निकल रही हैं तो कुछ को बुखार हो रहा है."

कहीं और इतना तूफान पैदा न होता लेकिन यह दिल्ली का मामला था, सो राजनैतिक हरकतों ने तुरंत जोर पकड़ लिया. इंकाई बहुमत वाले नगर निगम की जमकर खिंचाई हुई. महामारी केंद्रीय सूचना और प्रसारणमंत्री हरकिशनलाल भगत के पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में फैली हुई थी. सबसे अहम बात कि उन झुग्गी बस्तियों और पुनर्वास कॉलोनियों पर सबसे ज्यादा कहर टूटा जो सत्ताधारी दल इंका का वोट बैंक माने जाते हैं. दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के ग्रामीण इलाके और यहां तक कि नई दिल्ली के कुछ साफ-सुथरे इलाके भी इस महामारी से प्रभावित हुए.

केंद्रशासित प्रदेश में इंका की मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सरकारी अकर्मण्यता को न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि पीड़ित इलाकों में सहायता शिविर भी शुरू कर दिए. भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया. शहर के इन गंदे इलाकों में घूमने वाले वे एकमात्र पार्टी अध्यक्ष नहीं थे. इंका के सर्वेसर्वा राजीव गांधी भी पुनर्वास कॉलोनी नंद नगरी की गंदगी, कीचड़ भरी गलियों में घूमे. हालांकि इस कॉलोनी की बदतर हालत को छिपाने के लिए अचानक विशेष चिकित्सा शिविर लगा दिए गए लेकिन कूड़े के ढेरों, मल-मूत्र और बदबू को छिपाना असंभव था.

राजीव नंद नगरी की हालत देख बहुत क्रुद्ध हुए. उनके दौरे के बाद घंटे भर में सारे अधिकारी सक्रिय हो गए. कंप्यूटर चलने लगे और हालात का जायजा लेने के लिए बैठकें होने लगीं. प्रधानमंत्री नतीजा चाहते थे. तुरंत दिल्ली की 44 पुनर्वास कॉलोनियों में जमी सारी गंदगी तीन दिन में हटानी थी, सभी

150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और महामारी हर दिन करीब 12 लोगों की बलि ले रही है

◆

सारा जोर टीके लगाने पर है जबकि मेडिकल किताबों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय है कि महामारी में टीके लगाना व्यर्थ है

2,086 सेप्टिक टैंकों को सात दिन में और 1,234 किमी लंबे नाले-नालियों को 15 दिन में साफ, दुरुस्त करना था. दिल्ली प्रशासन के चिकित्सा विभाग को 'टीका लगाओ' अभियान शुरू करने का आदेश दिया गया. पूरे शहर के प्रभावित इलाकों में 9.6 लाख लोगों को— जो कि शहर की कुल आबादी की 12 फीसदी हैं— एक हफ्ते के भीतर हैजे का टीका लगाया जाना था.

दिन भर में दर्जनों बैठकें होतीं. महापौर मोहिंदर सिंह साथी शाम 4 बजे टाउन हाल में बैठक की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

घरों के बाहर कूड़े के ढेर के इर्दगिर्द बच्चे खेलते रहते हैं. खुली नालियां अलग गंदगी फैलाती हैं

◆

लोगों की शिकायत है कि सार्वजनिक शौचालयों की सफाई नहीं होती. पुनर्वास कॉलोनियों की देखभाल कौन करे इस पर एमसीडी और डीडीए लड़ती रही है

अध्यक्षता करते, मुख्य सचिव के.के. माथुर शाम 5 बजे सचिवालय में एक दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते और उपराज्यपाल हरकिशनलाल कपूर शाम 7 बजे राजभवन में बैठक करते. केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने तो दिन भर में दो-दो बैठकें तक बुलाईं. बाद में प्रधानमंत्री की सचिव सरला ग्रेवाल भी बैठकें लेने लगीं. पिछले हफ्ते शहर के अधिकारी हलाल किए जाने वाले मुर्गों की तरह लग रहे थे. वे सुबह से देर रात तक हड़बड़ी में रहते. प्रधानमंत्री के सक्रिय होते ही उनमें आतंक फैल गया. एक वरिष्ठ प्रशासनिक नौकरशाह बार-बार यही दुहरा रहा था, "मेरी तो नौकरी चली जाएगी."

लेकिन कोई भी अफसर इस सवाल का जवाब देता नहीं दिखा कि संकट फैलने से पहले वे अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे थे. आंत्रशोथ के मामले हर साल बढ़ जाते हैं. पिछली जुलाई में 6372 मामले हुए और उससे पहले की जुलाई में 9140 मामले. पिछले साल आंत्रशोथ से 123 लोग मरे. यह संख्या उससे पहले वाले वर्ष में मरने वालों की संख्या (90) से कहीं ज्यादा थी.

लेकिन पिछले पखवाड़े कोई भी अफसर यह नहीं बता सका कि शहर के लोगों के स्वास्थ्य की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है. एक अफसर ने कहा, "आप हमारा काम देख लीजिए." केंद्रशासित प्रशासन का कहना था कि उसकी जिम्मेदारी तो उसके अधीन आने वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तक सीमित है. कार्यकारी पार्षद (स्वास्थ्य) बंसीलाल चौहान का कहना था कि आम लोगों के स्वास्थ्य कार्यों की देखरेख करना उनका काम नहीं. उन्होंने कहा, "मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता. एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) से पूछिए."

और नगर निगम सारा दोष दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मत्थे मढ़ने में व्यस्त था. भ्रष्टाचार के इन भारी-भरकम गढ़ों को अपनी जिम्मेदारी बेशर्मी से एक दूसरे के सिर मढ़ने की कोशिश करते देख सारा शहर तमतमा रहा था. पुनर्वास कॉलोनियों की देखभाल कौन करे, इस पर इन दोनों संस्थाओं में अरसे से विवाद था. अखिरकार इसी साल 1 जून को इनकी जिम्मेदारी डीडीए से लेकर एमसीडी को सौंपी गई.

निगमायुक्त पी.पी. चौहान ने कहा, "ये कॉलोनियां निगम को सौंपे जाने के वक्त बदतर हालत में थीं. हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि पिछली बार इन्हें कब साफ किया गया." उधर डीडीए का कहना था कि ये कॉलोनियां अच्छी हालत में निगम को सौंपी गई थीं.

इस तर्क-वितर्क के बावजूद स्पष्ट है कि दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह नाकाम रहे. डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि प्राधिकरण सफाई कर्मचारियों से काम करवाने में विफल रहा. पुनर्वास कॉलोनियों के लिए रखे गए 2,000 पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी (1000 रु. से कुछ ज्यादा पाने वाले) काम ही नहीं करते. इसके बावजूद डीडीए के उपाध्यक्ष ओम कुमार ने ठेके के सफाई कर्मचारियों के लिए बनाई गई समानांतर प्रणाली मार्च में खत्म कर दी. उनकी दलील थी कि जून में एमसीडी को सौंपे जाने के पहले नियमित सफाई कर्मचारियों को काम शुरू कर देना है.

ताज्जुब की बात तो यह है कि दोनों ही पैसे की कमी का रोना रोते हैं. डीडीए के एक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकारी कहते हैं, "वर्षों से रखरखाव का काम करते हुए हम दिवालिया हो गए." एमसीडी भी सीमित धन का तर्क उस समय तक देती रही जब तक कि 21 जुलाई को उसके पास केंद्र से इन कॉलोनियों के लिए 10 करोड़ रु. का चेक नहीं पहुंच गया. लेकिन अधिकारियों का यह भी कहना है कि मार्च में दिए गए 4.86 करोड़ रु. से एमसीडी इन कॉलोनियों के लिए रखरखाव के उपकरण खरीद सकती थी.

बहाने तो अनंत थे. लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि इस शहर को, जिसे कि कुछ राज्यों से भी ज्यादा पैसा मिलता है, सफाई जैसी बुनियादी सुविधा भी क्यों नहीं मुहैया कराई जा सकी. एक बड़े अधिकारी ने माना, "मुझे संदेह है कि सरकार इसका कोई संतोषजनक जवाब दे पाएगी." 652 झुग्गी बस्तियों के बारे में इस अफसर का आसान-सा जवाब था, "ये बस्तियां कानूनी नहीं हैं." 13 लाख मर्दों, औरतों और बच्चों वाली इन बस्तियों के लिए यह दलील तो अति ही है.

लेकिन सरकार द्वारा बसाई गई पुनर्वास कॉलोनियों की इतनी आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती. इनमें से 35 कॉलोनियों को निगम का पानी मिल गया है लेकिन बाकी कॉलोनियां जस की तस ही हैं. प्रधानमंत्री ने और चार कॉलोनियों में निगम के पानी की सप्लाई का आदेश दिया है. अभी तक एमसीडी यह सब करने से बचती रही है. डीडीए के आयुक्त (झुग्गी बस्ती) मंजीत सिंह कहते हैं कि पिछली सर्दियों में जब 2,000 नए हैंडपंप लगाने का फैसला किया गया तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि यदि निगम पाइप वाला पानी मुहैया कराए तो हैंडपंप के बदले नलके लगाए जाएं. वे कहते हैं, "निगम वालों ने जवाब दिया कि उनके पास पानी नहीं है."

निवासियों की शिकायत है कि उनके सार्वजनिक शौचालयों और नाले-नालियों की सफाई के लिए वर्षों से कोई आया ही नहीं. नंद नगरी के 48 वर्षीय ओम प्रकाश ने कहा, "शौचालय इतने भर गए हैं कि मल-मूत्र सड़कों पर बह रहा है. इन शौचालयों की दो साल से सफाई नहीं हुई है." मकान के बाहर सड़ते कूड़ों का ढेर पड़ा रहता है और छोटे-छोटे बच्चे उनके चारों तरफ खेलते रहते हैं. मकानों के पीछे बदबूदार नाली भी बहती है. झुग्गी बस्तियों के इन पूर्व निवासियों के लिए बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों की हालत इतनी बुरी है कि उन्हें देखते ही उल्टी हो जाए.

चूंकि यह दिल्ली का मामला था और वोट बैंक इसकी चपेट में आए थे लिहाजा नेता लोग तुरंत हरकत में आ गए

◆

शहर के अधिकारी हलाल किए जाने वाले मुर्गों की तरह लग रहे थे. प्रधानमंत्री के सक्रिय होते ही उनमें भारी आतंक फैल गया

यही मैला बारिश के पानी से मिलकर भू-जल में जा मिलता है. दिल्ली के पूर्वी इलाकों में भू-जल का स्तर काफी ऊंचा है. इसका नतीजा क्या होता है? बनवारी लाल (52) बताते हैं, "मेरे हैंडपंप के पानी से बदबू आती है. कभी-कभी तो पंप का पानी नाली के पानी जैसा दिखता है."

पिछले पखवाड़े प्रशासन सुलभ शौचालय की व्यवस्था शुरू करने के लिए भाग-दौड़ करता रहा. लेकिन शहर के योजनाकार कहते हैं कि मामला किसी भी तरह के सार्वजनिक शौचालय से हल नहीं हो सकेगा, खासकर तब जब उसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा हो.

सार्वजनिक शौचालयों के इर्दगिर्द कीचड़ पड़ा रहता है. इसलिए पीलिया और टायफाइड के साथ आंत्रशोथ और हैजे का फैलना कोई हैरत की बात नहीं. इन रोगों में हैजा सबसे भयंकर है क्योंकि इसका रोगी एक दिन में परलोक सिधार जाता है. इसमें लगातार दस्त होते हैं. नतीजतन शरीर में पानी की कमी हो जाती है. आजादी से पहले हर साल हजारों लोग हैजे से मर जाते थे. 1950 में भी पूरे देश में इस रोग से 86,997 लोग मरे थे. 1970 में यह आंकड़ा 3801 था और 1980 में 309.

इसका एकमात्र इलाज है चीनी और चुटकी भर नमक का घोल पीते रहना. इसलिए यदि इस घोल का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया होता तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी. इसके बजाय सारा जोर टीका लगाने पर दिया जा रहा है जबकि चिकित्साशास्त्र की किताबों में साफ-साफ लिखा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि महामारी के समय टीके लगाना फ़िजूल की कसरत है. इसका कोई फायदा नहीं.

'टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव ऐंड सोशल मेडिसीन' के मुताबिक, "महामारी के नियंत्रण में टीकों की कोई अहमियत नहीं है." इनके इस्तेमाल से पेचीदगियां ही बढ़ सकती हैं. किताब में लिखा है, "कई देशों में सामूहिक रूप से टीके लगाने के बाद एक और गंभीर समस्या— सीरम हेपाटाइटिस (रक्तिम यकृत शोथ) उभरी है."

दिल्ली के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को सांत्वना की सख्त जरूरत है. दोनों तरफ से उनकी खिंचाई हो रही है. नौकरशाह और सत्तारूढ़ नेता ऊपर से मिली झाड़ पचा नहीं पा रहे हैं, वहीं जनारोष भी कम नहीं है. दिल्ली के लोग इस कहर के लिए कारणीभूत अकर्मण्यता, उदासीनता और भ्रष्टाचार से ही नहीं बल्कि बहानेबाजी और अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर मढ़ने की तिकड़मों से भी खफा हैं. —डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दार्जिलिंग

अमन की आहट

समझौता सभी पक्षों पर निर्भर

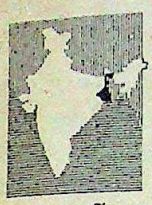

भारत में हिंसक आंदोलनों का स्वरूप कुछ ऐसा है कि वे आशा-निराशा के भंवर में डूबते-उतराते रहते हैं. तीन साल से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चल रहा हिंसक आंदोलन भी इसका अपवाद नहीं. पिछले दिनों में चार बार यह समस्या सुलझाव के मुकाम पर पहुंचकर अनिश्चितता और हिंसा के नए भंवर में घिरती गई है. पिछले पखवाड़े इस पहाड़ी क्षेत्र से जो खबर आई वह दार्जिलिंग की चाय के समान ही महक भरी थी.

इस बार केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) के प्रमुख सुभाष घीसिंग को बातचीत के लिए तैयार करने में कामयाब रहे. इस त्रिपक्षीय बातचीत के नतीजे भी नाटकीय रहे. घीसिंग पर्वतीय विकास परिषद की योजना के तहत दार्जिलिंग को सीमित स्वायत्तता देने के प्रस्ताव पर गौर करने के लिए राजी हो गए. इससे पहले वे स्वतंत्र 'गोरखालैंड' से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे. लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखीं: 'सरकारी आतंकवाद रुके, पुलिस के छापे बंद हों, सीआरपी को वापस बुलाया जाए, उग्रवादी नेताओं को घूमने-फिरने की आजादी दी जाए, बंदियों को रिहा किया जाए और पर्वतीय विकास परिषद में 'गोरखा' शब्द जोड़ा जाए. वक्त की जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री बसु ने सारी शर्तें मान ली. पश्चिम बंगाल के गृहसचिव एन. कृष्णमूर्ति ने कहा, "अब समझौते की संभावनाएं बढ़ गई हैं."

प्रशांत पंजियार

(बाएं से) बूटा सिंह, बसु, घीसिंग: शांति की कोशिश

घीसिंग और बसु दोनों अपनी मजबूरियों के कारण ही राजी हुए. घीसिंग को आंदोलन अपने हाथ से फिसलता लग रहा था. उधर बसु नहीं चाहते कि दार्जिलिंग समस्या उनके लंबे राजनैतिक जीवन पर कोई दाग बन जाए. उन्हें यह भी गवारा नहीं कि ग्यारह साल सत्ता में रहे वाममोर्चे के सामने अगले चुनाव में जब यह समस्या चुनौती बनकर आए तो उसका राजनैतिक फायदा इंका को मिले.

जैसे ही राज्य सरकार ने समस्या से सुलटने की तैयारियां शुरू कीं, घीसिंग भी सक्रिय हो गए. दिल्ली की सफल वार्ता के बाद उन्होंने आर.पी. वैबा और सी.के. प्रधान जैसे अपने सभी प्रमुख समर्थकों को पिछले महीने दार्जिलिंग बुलाया. अड़ियल उग्रवादियों को लगभग धमकाते हुए घीसिंग ने उनसे भविष्य में निष्ठावान और अनुशासित बने रहने का वायदा भी ले लिया. अपने सहयोगियों के रवैये से उत्साहित घीसिंग बोले, "यदि राज्य सरकार की नीयत साफ होती तो नौ महीने पहले यह समझौता हो गया होता. मैं तो अब भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं. शर्त यही है कि बसु नई दिल्ली में किए अपने वादों से न फिरें."

लेकिन ऐसा नहीं कि घीसिंग के लोग उनका विरोध नहीं कर रहे. जीएनएलएफ के सहायक महासचिव और कलिपोंग के एक प्रमुख उग्रवादी छत्री सुब्बा ने न केवल घीसिंग की दार्जिलिंग बैठक में आने से इनकार कर दिया बल्कि पर्वतीय विकास परिषद के सुझाव को भी नामंजूर कर दिया.

सभी फोटो: सैबल दास

(बाएं) जीएनएलएफ की बैठक में घीसिंग और उत्सुक लोग: शंकाएं कायम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha[illegible]ar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गोरखा राष्ट्रीय छात्र मोर्चा और गोरखा राष्ट्रीय महिला संगठन जैसे मोर्चे के महत्वपूर्ण घटकों ने भी शुरू में पवर्तीय विकास परिषद के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था लेकिन बाद में थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उन्होंने इस बिना पर इसे मंजूर कर लिया कि पूर्ण राज्य की ओर यह पहला कदम है.

घीसिंग ने भी यह मांग दुहराई, "अलग राज्य की मांग हम कभी नहीं छोड़ेंगे." लेकिन इसमें प्रतिबद्धता कम, दिखावा ज्यादा था क्योंकि सी.के. प्रधान की अगुआई में उनके खास लोग सुब्बा और उसके आदमियों को पटाने में लग गए थे. लेकिन सुब्बा झगड़ने का मन बना चुके थे. इसलिए बात बनी नहीं. इन दोनों गुटों की झड़पों में अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं.

समस्याएं बसु के सामने भी आईं, वाम-मोर्चे के एक प्रमुख घटक फारवर्ड ब्लॉक को पर्वतीय विकास परिषद में 'गोरखा' शब्द जोड़े जाने पर घोर आपत्ति थी. कई विपक्षी दलों ने भी प्रस्तावित परिषद की आलोचना की. इनमें भाजपा प्रमुख है. लेकिन बसु ने पिछले पखवाड़े वादा किया कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ही वे सभी दलों की एक बैठक बुलाएंगे.

लेकिन कुछ शंकाएं बाकी हैं. पर्वतीय विकास परिषद में 'गोरखा' शब्द जोड़े जाने की मांग के अलावा जीएनएलएफ ने पर्वतीय परिषद में गोरखा सिलीगुड़ी के आसपास के मैदानी इलाके को मिलाए जाने की भी मांग रखी है. फिर घीसिंग इस बात की 'संवैधानिक गारंटी' चाहते हैं कि राज्य सरकार मनमर्जी से पर्वतीय परिषद को भंग न कर सके. इसके अलावा पर्वतीय विकास परिषद विधेयक तैयार होने तक अंतरिम परिषद के गठन की उनकी मांग भी है.

घीसिंग चेतावनी के स्वर में कहते हैं, "यदि अंतरिम परिषद नहीं बनाई गई तो पहाड़ियों में हिंसा भड़क उठेगी और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा." उनका मानना है कि अंतिम फैसला तो अब राज्य सरकार को ही करना है.

अब अहम सवाल यह नहीं रह गया है कि इस मामले में अगला कदम कौन उठाए. कई महीनों की टालमटोल के बाद तीनों पक्ष—जीएनएलएफ, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र—ही अपने-अपने पांसे फेंक चुके हैं. नतीजा अब दो बातों पर निर्भर करता है—इस तनावग्रस्त जिले में शांति स्थापित करने के उनके इरादे कितने नेक हैं और दूसरे, इस विवादास्पद समझौते को लागू करने का उनमें कितना राजनैतिक संकल्प है.

—**कमलजीत रतन**, दार्जिलिंग में

गुजरात

होश में लाने का टेढ़ा उपाय

पुलिसवालों की बगावत से चौधरी को बने रहने का मौका मिला

चौबीस जुलाई को सुबह उठते ही अहमदाबाद के बाशिंदे यह देखकर सकते में आ गए कि सेना की कुमाऊं रेजीमेंट के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अर्ध-सैनिक बलों की टुकड़ियां शहर में गश्त लगा रही हैं. अगले दिन चूंकि बकरीद थी इसलिए कई लोग 1985 की बेमिसाल सांप्रदायिक हिंसा की याद से सिहर उठे.

लेकिन किसी को कल्पना भी नहीं थी कि अमरसिंह चौधरी सरकार ने बेकाबू होते पुलिसवालों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए सुरक्षा बलों को न्यौता है. अपनी मांगों को लेकर अर्से से खदबदाते पुलिसवालों को ठीक करने के लिए सरकार आधी रात को अचानक हरकत में आई. उसने इंस्पेक्टरों, सब-इंस्पेक्टरों, हवलदारों और सिपाहियों की यूनियनों की मान्यता रद्द करके उनके 54 नेताओं को नौकरी से निकाल दिया. इसी के साथ अनुशासनहीनता के आरोपों में उनके सात नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारशुदा नेताओं में चार यूनियनों की समन्वय समिति के उग्र स्वभाव वाले संयोजक और असरदार नेता अशोक भट्ट भी थे.

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तब तक राज्य पुलिस के 34 शस्त्रागारों और पुलिस संचार व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया था. राज्य सरकार की खुशकिस्मती से इस कार्रवाई से वैसी गंभीर प्रतिक्रिया नहीं हुई जिसका अंदेशा था. 24 जुलाई को अहमदाबाद के नरोड़ा में एकमात्र गंभीर घटना उस वक्त हुई जब भट्ट की गिरफ्तारी का विरोध करती भीड़ पर काबू पाने के लिए केरिपुब को गोली चलानी पड़ी.

अहमदाबाद में कुछ जगहों पर उत्तेजित पुलिसवालों ने दुकानों में आग लगा दी. वडोदरा में पथराव और आगजनी की कुछ घटनाओं को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में शांति रही. सरकारी कार्रवाई के विरोध में अहमदाबाद के 24 थानों में से आधे और राजकोट के छह में से दो थानों के पुलिसवाले ड्यूटी छोड़कर चले गए.

दरअसल पुलिसवाले सरकार की अचानक कार्रवाई से सकते में आ गए. जैसा कि एक पुलिसिए ने कहा, "बगावत करवाने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त था." हालांकि बाद में पुलिसवाले संभल गए. यूनियन नेताओं ने सरकारी कार्रवाई के विरोध में

भवान सिंह

उनसे हड़ताल करने की अपील की तो समूचे राज्य की पुलिस हड़ताल पर चली गई. उनका हौसला बंधा भट्ट समेत गिरफ्तार यूनियन नेताओं की न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा रिहाई से. दंडाधिकारी ने फैसला दिया कि पुलिस नेताओं पर लगाए गए आरोप अपर्याप्त हैं. हालांकि भट्ट को अगले ही दिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. चारों यूनियनों के नेताओं ने साझा बयान में कहा, "पुलिसवाले तब तक अपने काम पर वापस नहीं आएंगे जब तक बर्खास्तगी के आदेश वापस नहीं ले लिए जाते. हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन इंसाफ मिलने तक जारी रहेगा."

पुलिसवालों की यूनियन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र—खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

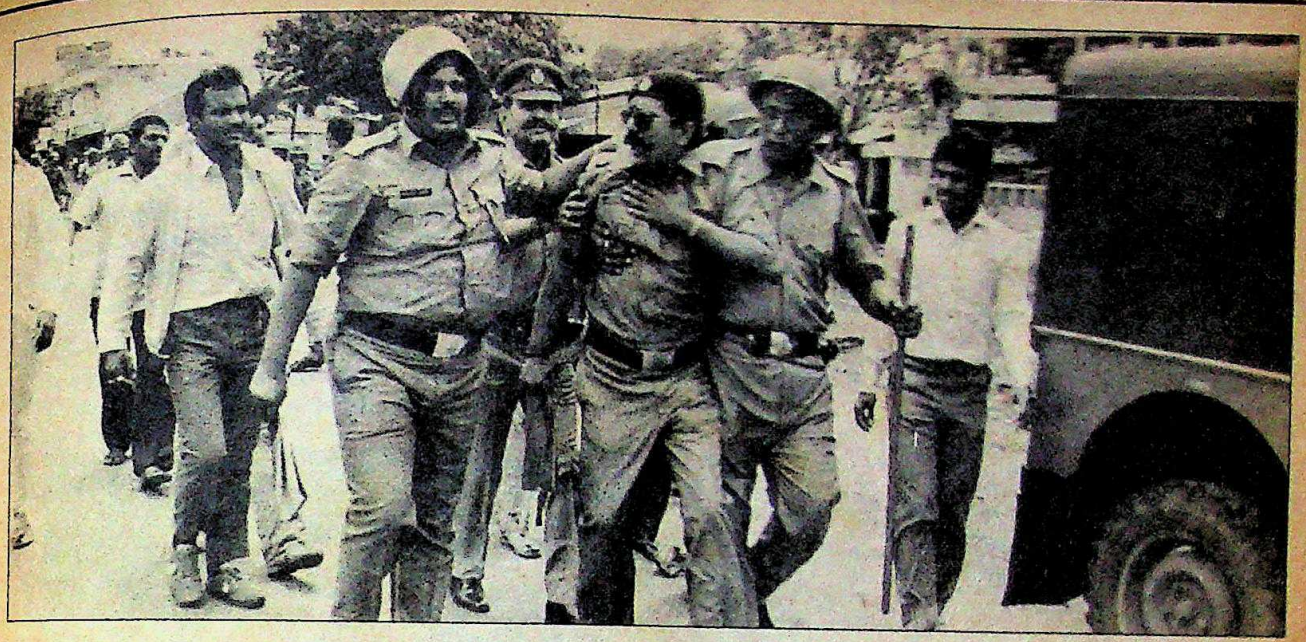

यूनियन के नेता अशोक भट्ट की गिरफ्तारी: अनुशासन का डंडा

"अनुशासनहीनता हद से बढ़ जाए तो कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं... अब सुलह करने का सवाल ही नहीं. हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया"

अमर सिंह चौधरी, मुख्यमंत्री

इस बयान की अगले ही दिन प्रतिक्रिया हो गई. अहमदाबाद के कम-से-कम 20 थानों के सिपाही हड़ताल पर चले गए. शहर के गोमतीपुर इलाके में उन्होंने दो बसों में आग लगा दी और दो दुकानें लूट लीं जिसकी वजह से अर्धसैनिक बलों को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

सबसे अहम बात यह रही कि आंदोलनकारियों को अप्रत्याशित हलकों से भी समर्थन मिला. भाजपा के विधायक अशोक भट्ट (यूनियन नेता अशोक भट्ट के नामराशि) ने कहा, "पुलिसवालों के खिलाफ गैरजरूरी कार्रवाई करके मुख्यमंत्री दिखाना चाहते हैं कि वे कितने सख्त हैं. लेकिन यह प्रयोग बेहद खतरनाक है." भाकपा के अशोक पंजाबी का कहना था, "यह कार्रवाई सरासर अलोकतांत्रिक है." 1986 में चौधरी को अपनी मांगें मानने के लिए मजबूर कर देने वाली राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के नेताओं ने भी हड़ताली पुलिसवालों को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की.

आंदोलन कुचलने की सरकारी नीति चौधरी और केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह समेत कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों के बीच मध्य जुलाई में शुरू हुई बैठकों का ही नतीजा थी. अधिकृत सूत्रों के अनुसार राज्य पुलिस में बढ़ती अनुशासनहीनता पर बूटा सिंह ने सख्त नाराजगी दिखाई थी. इसलिए पुलिसवालों के पर कतरने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक योजनाएं बनाई गईं. चौधरी ने कहा, "अनुशासनहीनता हद से बढ़ जाए तो उसे दबाने के लिए कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं."

मुख्यमंत्री की बात में दम है. 1985 के सांप्रदायिक उन्माद में पुलिसियों के एक गुट ने गुजराती दैनिक 'गुजरात समाचार' के दफ्तर पर धावा बोलकर लाखों की संपत्ति तबाह कर डाली थी. पिछले साल वार्षिक रथयात्रा की पूर्व-संध्या पर उनकी हड़ताल तो अनुशासनहीनता की हद ही थी. पिछले स्वतंत्रता दिवस पर तो सरकारी आयोजनों का बहिष्कारकर कुछ पुलिसवालों ने अलग झंडा भी फहराया. अंततः सरकार ने अस्थायी समझौता कर उनकी कुछ मांगें मान लीं.

ताजा संकट पुलिसवालों के पुराने आंदोलनों की ही पुनरावृत्ति है. इस साल के शुरू में उनकी यूनियनों ने राज्य सरकार को 20 सूत्री मांगपत्र दिया और धमकी दी कि यदि मांगें न मानी गईं तो वे हड़ताल कर देंगे. ज्ञापन में सिर्फ आठ घंटे की ड्यूटी, सब-इंस्पेक्टरों और इंस्पेक्टरों तक को सरकारी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करने पर अतिरिक्त पैसा, दिन में आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने पर भी अतिरिक्त पैसा और समयबद्ध पदोन्नति की मांगें भी थीं.

मामला तब बिगड़ गया जब आंदोलनकारी पुलिसवालों ने राज्य की रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी को पंजाब जाने का सरकारी आदेश न मानने के लिए भड़काया. उनकी यह हरकत सरकार को कड़ा कदम उठाने को बाध्य करने के लिए काफी थी. पर चौधरी चाहते तो पुलिसवालों की कुछ मांगें मानकर संकट टाल सकते थे. उन्होंने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि पुलिसवालों की 22 मांगों में से कुछ, खासकर भत्ता बढ़ाने से संबंधित मांगें, जायज थीं.

सरकारी कार्रवाई से अब जो संकट पैदा हो गया है वह आसानी से दूर नहीं होगा. 24 जुलाई को तो पुलिस विद्रोह अहमदाबाद और राजकोट तक सीमित था लेकिन अगले दिन तीन और जिलों के पुलिसवाले भी बागी हो गए. गांधीनगर में तो मंत्रियों के सुरक्षा प्रबंध संभालने वाले पुलिसवाले भी ड्यूटी छोड़कर चले गए. इसके बावजूद चौधरी केंद्र का वरदहस्त पीठ पर होने के कारण विद्रोह दबाने के लिए कृतसंकल्प दिखते हैं. वे कहते हैं, "अब सुलह करने का सवाल ही नहीं उठता. पुलिस अनुशासनहीनता को हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया."

लेकिन हो सकता है चौधरी कोई ऊंची चाल चल रहे हों. ऐसे समय जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के असंतुष्ट उनके जाने की आस लगाए बैठे हों, पुलिस बगावत से उत्पन्न गड़बड़ियों के चलते वे कुछ दिन और सत्ता में बने रह सकते हैं.

—उदय माहूरकर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

रक्तबीज अभी जिंदा है

सुक्खा के मारे जाने से हालात में ज्यादा तब्दीली नहीं

पंजाब में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही लड़ाई भी अजीब है—हालात चाहे जितने बदलें, नजारा जस का तस ही रहता है. एक 'सबसे दुर्दांत' आतंकवादी को मार गिराने के बाद पुलिस फतह का एलान कर देती है पर आतंकवादी फिर हल्ला बोलते हैं और पुलिस के दावे झूठे साबित हो जाते हैं.

इसीलिए 12 जुलाई को जब सुरक्षा बलों ने सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा सिपाही उर्फ 'जनरल' लाभ सिंह को मार गिराया तो इस मामले में पुलिस ने काफी सावधानी बरती. हालांकि सुक्खा हत्यारों के सबसे खतरनाक गिरोह खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) का निर्विवाद अगुआ था पर वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने 'आतंकवाद की चूलें हिल गई हैं' जैसा दावा करने वाला कोई बयान नहीं जारी किया.

पिछले छह महीनों में हथियारबंद आतंकवादियों से पुलिस की 231 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 182 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए और तकरीबन 2,000 संदिग्ध आतंकवादी व उनके सक्रिय समर्थक पकड़े गए. पुलिस द्वारा वांछित आतंकवादियों की सूची में 'ए' श्रेणी के जो 22 आतंकवादी थे उनमें तकरीबन 12 एक साल में मार गिराए गए हैं. पुलिस रिकार्ड के मुताबिक इस दौरान इस फेहरिस्त के 'बी' श्रेणी के 100 में तकरीबन आधे आतंकवादियों का भी सफाया किया जा चुका है. लेकिन हत्यारों के आतंकवादी अभियान पर कोई असर नहीं पड़ा. इन्हीं छह महीनों में आतंकवादियों के विभिन्न गुटों ने 1,203 बेकसूर लोगों और सुरक्षा बलों तथा पुलिस के 63 जवानों की हत्या कर दी.

हालांकि पुलिस महानिदेशक के.पी.एस. गिल इस बात की कसम खाए बैठे हैं कि "हर उस आतंकवादी को पकड़ा जाए जो सक्रिय है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो." लेकिन राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय के सलाहकार जूलियो फ्रांसिस रिबेरो स्वीकार करते हैं, "लाभ सिंह की मौत आतंकवादियों के लिए सदमा तो है पर कोई और स्वयंभू जनरल उसकी जगह ले चुका होगा." खुफिया रिपोर्टें भी रिबेरो की बात की ताईद करती हैं. खास तौर पर केसीएफ और काफी हद तक बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों में वैसे ही कट्टर हत्यारों की दूसरी पंक्ति भी तैयार है.

केसीएफ 1986 तक अलग-अलग गुटों का ढीला-ढाला संगठन था. लाभ सिंह ने इसे एक ऐसे संगठित अपराधी गिरोह में तब्दील कर दिया जिसके अपने पदाधिकारी हैं. इस गिरोह का दर्शन है 'खालिस्तान' की अस्पष्ट मांग. पर इसका असल मकसद लूटमार, हत्याओं और डकैती से पैसे वसूलना है.

लाभ सिंह का आपराधिक जीवन बैंक डकैतियों से शुरू हुआ. अक्तूबर 1986 में उसके गिरोह ने लुधियाना के एक बैंक से 10.23 लाख रु. लूटे. फरवरी 1987 में इस गिरोह के 22 सदस्यों ने लुधियाना के बैंक में देश की सबसे बड़ी डकैती डाली और 5.70 करोड़ रु. लूट लिए. अव्वल दर्जे का आतंकवादी होने के साथ-साथ लाभ सिंह कुशल संगठनकर्ता भी था. उसने विभिन्न इलाकों में छह 'लेफ्टिनेंट जनरल' नियुक्त करके केसीएफ को केंद्रीकृत बना दिया. 'लेफ्टिनेंट जनरल' के मातहत हर जिले में एक-एक 'एरिया कमांडर' है. अगर कभी 'ले. जनरल' मारा या पकड़ा जाए तो तुरंत ही 'एरिया कमांडर' उसकी जगह ले लेता है.

आंतरिक संरचना के मामले में केसीएफ दूसरे संगठनों से ज्यादा पुख्ता है. इसके पास सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार भी हैं.

बी.पी. कपूर

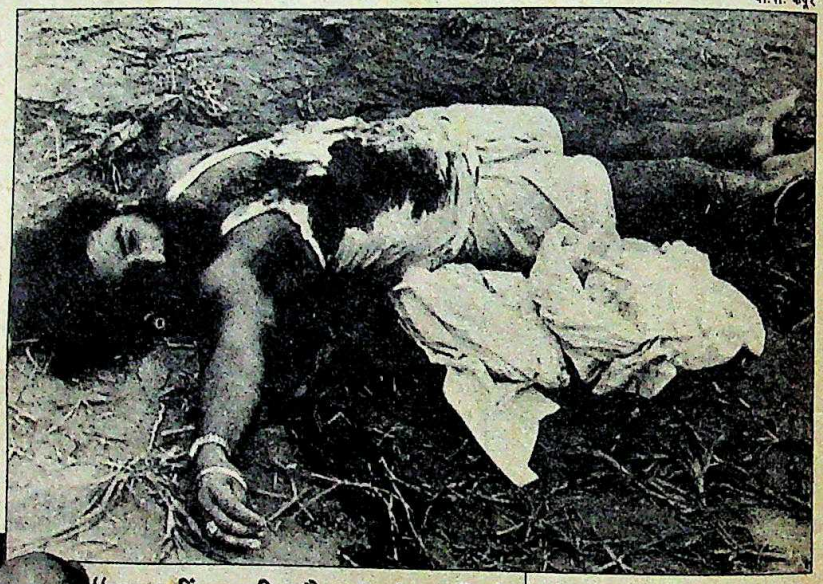

मुठभेड़ में मरा लाभ सिंह

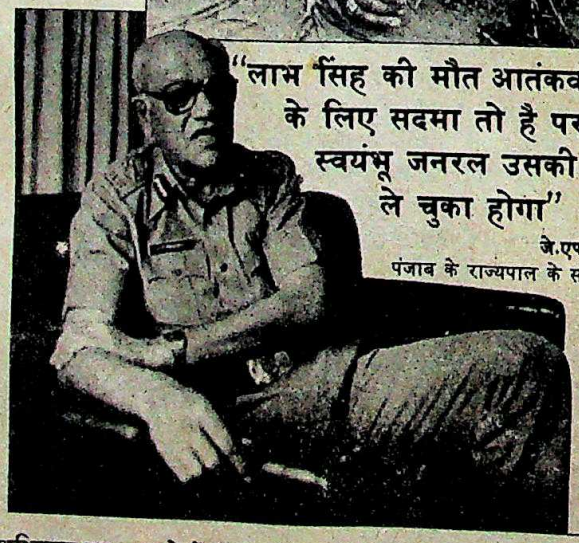

"लाभ सिंह की मौत आतंकवादियों के लिए सदमा तो है पर कोई स्वयंभू जनरल उसकी जगह ले चुका होगा"

जे.एफ. रिबेरो
पंजाब के राज्यपाल के सलाहकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक केसीएफ के पास कारों और ट्रकों का अपना जखीरा भी है. साथ ही इसने प्रमुख शहरों में जमीन-जायदाद में भी पैसा लगा रखा है. पिछले साल ही पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों से कई कारें और 20 लाख रु. से भी ज्यादा की संपत्ति बरामद की थी. बताया तो यह भी जाता है कि पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों के परिवारों में केसीएफ ने

चार्ट: बी.के. शर्मा

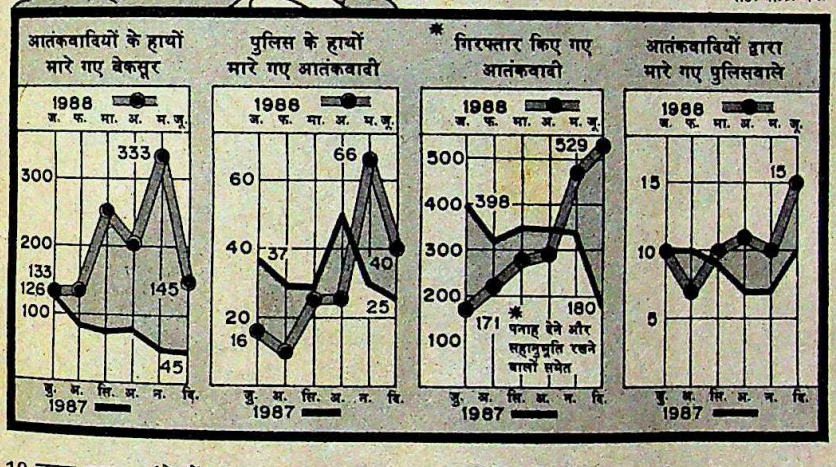

10 लाख रुपए बांटे हैं.

पिछले दो वर्षों में केसीएफ ने स्वर्ण मंदिर के भीतर अपनी खासी पकड़ बना ली थी पर इस साल मई में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद से उसकी पकड़ ढीली हो गई. अब यह गिरोह पूरी तरह भूमिगत हो गया है. पिछले साल पुलिस मुठभेड़ों में दूसरे आतंकवादी गिरोहों के मुकाबले केसीएफ के ज्यादा लोग मारे गए हैं. इसके बावजूद दूसरे गिरोहों से इसके हाथ ऊपर ही रहे क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या ज्यादा है.

केसीएफ की मजबूती की एक वजह यह भी हो सकती है कि इसमें ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएसएफ) के पढ़े-लिखे युवक बड़ी संख्या में सक्रिय हैं. केसीएफ के सबसे ताकतवर तीन लोग चरनजीत सिंह चन्नी, गुरशरण सिंह गामा और दलजीत सिंह बिट्टू स्नातक हैं. यह तिकड़ी और सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के नेता गुरजीत सिंह (यह भी स्नातक है) ही संभवतः लाभ सिंह की जगह लें.

लाभ सिंह जैसे शातिर सरपरस्तों की जगह भी इतनी आसानी से भर जाती है इस तथ्य ने वरिष्ठ अफसरों और पुलिसवालों को आतंकवादियों के प्रति अपनी नीति पर फिर से विचार के लिए मजबूर कर दिया है. रिबेरो भी कहते हैं, "पुलिस आतंकवाद से जूझ भर सकती है, उसका हल नहीं निकाल सकती." पर "जो लोग बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं उनके खिलाफ गोली का जवाब गोली वाली नीति तो चलती रहेगी."

हालांकि पुलिस के सूत्र तो कहते हैं कि आतंकवादी संगठनों के प्रति आम जनता की सहानुभूति खत्म होती जा रही है पर इसके लक्षण कम ही दिखते हैं. असल में जनता के एक बहुत बड़े तबके के अलग-थलग पड़ जाने की एक वजह तो भरपूर अधिकारों से लैस पुलिस भी हो सकती है. अक्सर इन अधिकारों का दुरुपयोग होता है और पुलिस ज्यादतियों, फर्जी गिरफ्तारियों और उत्पीड़न के कई उदाहरण मिलते हैं. रिबेरो भी, बताया जाता है कि अब कई 'गोपनीय' बैठकों में "पुलिस में हर तरफ फैले भ्रष्टाचार" की बात उठा चुके हैं.

पुलिस के दावों के विपरीत इस बात के काफी सबूत हैं कि आतंकवादी संगठन अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं. लाभ सिंह के मारे जाने के बाद सीमावर्ती जिलों में कई जगह बंद हुए. उसकी भोग रस्म में बड़ी तादाद में लोग जुट आए.

इससे भी बुरी खबर यह है कि वासन सिंह और गुरबचन सिंह मनोछल जैसे आतंकवादियों ने हाल ही में गांवों में एक अपील जारी की है कि हर परिवार उनके 'कारज' के लिए अपना एक-एक बेटा 'दान' करे. यही पंजाब की सबसे बड़ी त्रासदी है—लाभ सिंह मारा गया पर आतंकवाद बदस्तूर जिंदा है.

—विपुल मुद्गल

मध्य प्रदेश

शौक भारी पड़ा

गोविंद नारायण सिंह मुश्किल में

किसी राज्यपाल के बोरिया-बिस्तर से इस तरह का सामान निकलना असामान्य है. पिछले पखवाड़े जब बिहार के राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह इंडियन एअरलाइंस के विमान से इंदौर हवाई अड्डे पर उतरे तो उनके सामान में दो गैरलाइसेंसी हथियार थे—एक बंदूक तथा एक रिवाल्वर. उन्होंने तुरंत ये हथियार जिलाधीश को सौंप दिए. इससे पहले जून के पहले हफ्ते में उनके बेटे इंका विधायक हर्ष सिंह ने अपने गृह जिले सतना में ऐसे ही नौ हथियार पुलिस के पास जमा कराए थे. इनके लाइसेंस नहीं थे.

इस परिवार के हथियारों पर हो-हल्ला तब हुआ जब राज्यपाल के गृहनगर रामपुर बघेलान के एक राजनैतिक कार्यकर्ता ने 2 जून को सतना के जिलाधीश को एक ज्ञापन दिया. इसमें अनुरोध किया गया था कि बिहार के राज्यपाल के भोपाल और रामपुर बघेलान के घरों में रखे हुए गैर-

गो.ना. सिंह: हथियारों का मामला

कृष्ण मुरारी किशन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाइसेंसी हथियार जब्त किए जाएं. दो दिन बाद हर्ष ने जब अपने पिता के निर्देश पर ये हथियार रामपुर बघेलान के पुलिस थाने में जमा कराए तब उन्होंने दावा किया कि इनके लाइसेंसों के नवीनीकरण के कागजात भोपाल के जिलाधीश के यहां पड़े हैं.

लेकिन भोपाल के जिलाधीश कार्यालय ने जब इन कागजात की जांच की तो पता चला कि राज्यपाल के इन 11 हथियारों के लाइसेंसों की तारीख तो 1983 में ही खत्म हो गई थी. राज्यपाल को तभी पास के किसी पुलिस स्टेशन में ये हथियार जमा करा देने चाहिए थे. पर उन्होंने गैरकानूनी ढंग से ये हथियार चार साल तक अपने पास रखे जो कि एक फौजदारी अपराध है. अपने गृह प्रदेश मध्य प्रदेश में ये वयोवृद्ध नेता शिकार और हथियारों में अपनी दिलचस्पी के लिए जाने जाते हैं.

इस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. उनका कहना है कि इन सारे हथियारों का जिक्र सरकारी दस्तावेजों में है. उन्होंने शायद इस बात का भी जिक्र किया है कि लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए 1986 में अर्जी दाखिल की गई थी. तबसे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और एक के बाद एक आने वाले मुख्य सचिवों को कई स्मरण पत्र भेजे पर लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हुआ. उनकी शिकायत है, "सरकार ने जवाब नहीं दिया."

लेकिन विवाद सिर्फ लाइसेंसों के नवीनीकरण तक ही सीमित नहीं रहा. कुछ हथियार जितने बोर के पाए गए उतने बोर के हथियार रखने पर पाबंदी है. अब सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं कि इस सत्ताधारी राजनीतिक ने इन हथियारों के लाइसेंस कैसे हासिल कर लिए. बाप-बेटे द्वारा जमा कराए गए इन हथियारों में 303 बोर की राइफल और एक कारबाइन भी है. नागरिकों को आम तौर पर इन हथियारों के लाइसेंस नहीं दिए जाते. तिवारी ने एक बयान में सरकार से मांग की है कि आर्म्स एक्ट के तहत राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे.

इस तथ्य के बावजूद कि राज्यपाल ने अर्जुन सिंह को चिट्ठी लिखी और दो और हथियार जमा कराए, कई लोग मानते हैं कि मामला खत्म नहीं होगा क्योंकि अर्जुन सिंह और उनके पुराने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी गोविंद नारायण सिंह के रिश्तों में अब पहले जैसी मधुरता नहीं रही. लगता है बंदूकों ने शिकारी को ही घायल कर दिया है.

—नरेंद्र कुमार सिंह

मानसून

इंद्र मेहरबान

रिकार्डतोड़ फसल की उम्मीद

आखिरकार इंद्र देवता मेहरबान हुए और ऐसे मेहरबान हुए कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया. पिछले साल का सूखा अगर शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा था तो इस साल का मानसून दशक का सबसे बढ़िया मानसून है. खरीफ की रिकार्डतोड़ फसल होने की उम्मीद बंधी है.

धुंआधार मानसूनी बारिश गुजरात में हुई तो सूखे से पीड़ित इस प्रदेश में आशा और उत्साह का संचार हो गया. पिछले साल गिर वन के शेरों को पानी के लिए वन रक्षकों ने छोटे-छोटे गड्ढों तक सीमित कर दिया था. लेकिन अब वे मगन हैं क्योंकि उनके पसंदीदा गड्ढे अब पानी से लबालब भर गए हैं. पश्चिमी कच्छ के रेगिस्तान में बारिश की वजह से 24 मीटर ऊंचे मिठी बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ा जिसकी वजह से इसकी दीवारें ढह गईं और निचाई वाले पांच गांव बाढ़ की चपेट में आ गए.

हालांकि मानसून ने अभी अपना आधा सफर तय किया है लेकिन मौसम के हिसाब से बनाए गए 35 में से 34 सब-डिवीजनों में या तो सामान्य अथवा उससे ज्यादा बारिश हो चुकी है. इसका एकमात्र अपवाद अरुणाचल है. यहां कम बारिश से लोगों ने राहत महसूस की.

यों तो इस साल केरल में मानसून पांच दिन पहले पहुंच गया लेकिन एकबारगी यह कमजोर नजर आया. दक्षिण तक तो यह हल्का रहा लेकिन पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तर-पूर्व के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए. मानसून की मूसलाधार बारिश उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में हुई. इसके बाद सूखे से त्रस्त राजस्थान और गुजरात राज्यों में भी तगड़ी बारिश हुई. इस तरह मानसून अपने वक्त से एक सप्ताह पहले ही पूरे देश पर छा गया.

फिलहाल कृषि भवन का माहौल खुशनुमा हो गया है. उनकी खुशी बिलावजह भी नहीं. रबी की फसल के रिकार्ड उत्पादन के बाद अच्छी बारिश ने रिकार्डतोड़ खरीफ की फसल की संभावनाएं पैदा कर दी हैं. धान की बुआई सामान्य तौर से हुई और पंजाब के किसानों ने एक पखवाड़े पहले ही बुआई पूरी कर ली. पिछले साल मूंगफली की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था

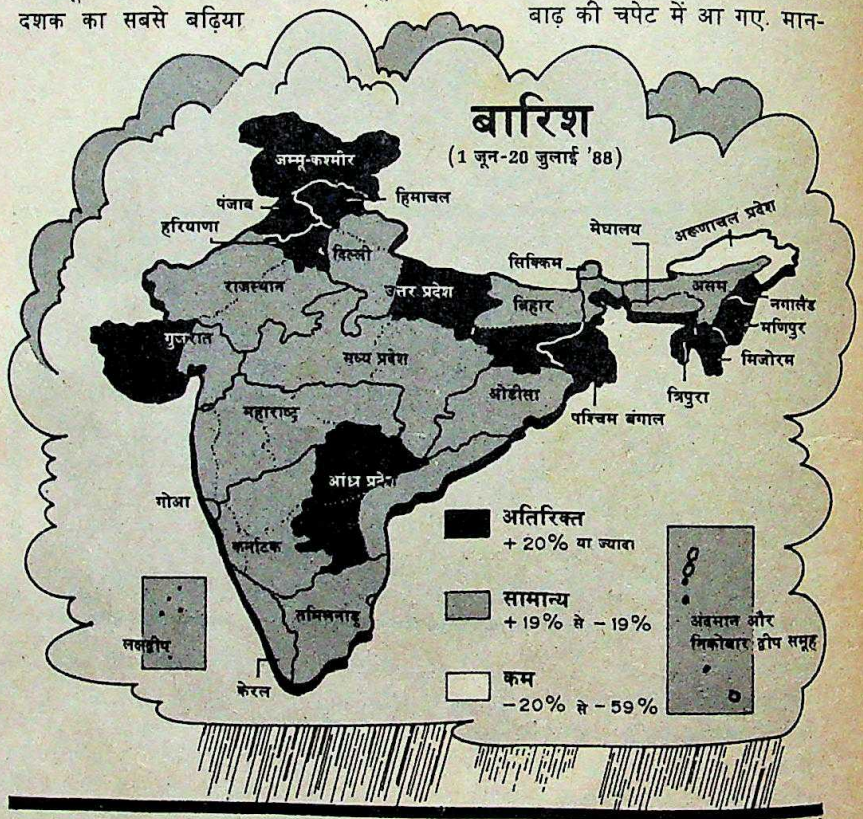

नक्शा: वी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन इस साल इसके अच्छे उत्पादन की उम्मीदें बंधी हैं. सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाले राज्य गुजरात में तकरीबन 75 फीसदी मूंगफली की बुआई पूरी हो गई. गन्ना उत्पादन के इलाके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी अच्छी फसल की सूचना है. एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने कहा, "शुरुआत बेहद अच्छी है. यदि अगस्त में भी अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी."

पिछले साल सूखे की वजह से खेतों में दरार पड़ने से अधिकारी परेशान थे. इस साल वे खतरे के निशान पार करती नदियों के जल स्तर को लेकर परेशान हैं. बिहार में आम तौर पर सामान्य रहने वाली कोसी, कमला बलान, अधवारा नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ा और आठ जिलों में बाढ़ आ गई. 30 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और तकरीबन 5 लाख लोग प्रभावित हुए. दरभंगा जिले में तो बाढ़ ने तमाम तटबंधों में दरार पैदा कर दी. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आसरा लेना पड़ा.

श्रीनगर में झेलम नदी का पानी तटबंध तोड़कर निकल आया. बाढ़ में फंसे हजारों असहाय लोगों को निकालने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी. बाकी स्थानों पर मुसीबत दूसरी शक्ल में आई. केरल के सबसे ज्यादा धान की पैदावार वाले इलाके कुट्टनाड के किसान इस बात से बेहद चिंतित थे कि अगर बाढ़ आई तो उनकी फसल नष्ट हो जाएगी. इडुक्की बांध का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से राज्य में एक साल से चली आ रही बिजली कटौती समाप्त कर दी गई. पिछले हफ्ते तक बारिश की वजह से कुल मिलाकर 170 लोगों की जानें गईं.

नई दिल्ली में बारिश ने असाधारण गरमी से छुटकारा दिलवाया और उड़ती धूल बैठा दी. बंबई में हर बार की तरह बारिश ने यातायात अवरुद्ध कर दिया जिसकी वजह से वाहनों की मीलों लंबी कतारें लग गईं. इसके नजदीक ठाणे जिले की छोटी नदियां जल्दी ही उफनने लगीं. कई घर बह गए और तकरीबन 10,000 लोग बेघर हो गए. लेकिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश से लोगों ने राहत ही महसूस की. गरमी के शुरू से पानी सप्लाई में चल रही 10 फीसदी कटौती समाप्त कर दी गई.

हालांकि देश के कृषि हलकों में अभी भी थोड़ा तनाव है. इंद्र देवता अगर अगस्त तक इसी तरह मेहरबान नहीं रहे तो किसानों की उम्मीदों पर थोड़ा पानी जरूर फिर जाएगा.

—राज चेंगप्पा

भारतीय पुलिस सेवा

शिकायत के स्वर

पक्षपात, अतिक्रमण से खफा

पुलिस संगठन ऐसे खाकीधारी संन्यासियों का झुंड बन गया है जो हमेशा डरते रहते हैं कि अगली शाम का भोजन नसीब होगा या नहीं, और सत्य का शोध करने की जिनकी संकल्पशक्ति मर चुकी है.

यह बयान पुलिस सिपाहियों के संघ या के.एफ. रुस्तमजी सरीखे बुजुर्ग पुलिसवाले का होता तो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होता. लेकिन जब इस तरह का बयान भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संघ की हाल में हुई बैठक में जारी किया गया तो सरकार के कान खड़े हो गए. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था, "अखिल भारतीय सेवाओं में इस तरह की आत्मालोचना असामान्य बात ही है. लेकिन हमारी चिंता यह है कि इसके साथ ही कानूनी याचिकाओं और विरोधपत्रों की बाढ़ आ गई है."

देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सबसे अहम हलके में हलचल बेहिसाब बढ़ गई है. इसका सबूत पिछले पखवाड़े तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की कार्रवाइयां हैं. दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त प्रीतम सिंह भिंडर, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के तेजतर्रार अधिकारी विनोद कृष्ण कौल और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दिग्गज डी.पी.एन. सिंह ने लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला कर लिया. उन्होंने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि उनसे जूनियर अधिकारियों को पदोन्नति देकर उनसे ऊपर कर दिया गया था. डी.वी.एल. रामकृष्ण राव को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का प्रमुख और टी. अनंतचारी को बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक बना दिया गया. सिंह और कौल दोनों राव की ही तरह 1957 बैच के आईपीएस हैं. लेकिन दोनों राव से सीनियर हैं. अनंतचारी की पदोन्नति की वजह से भिंडर खफा हैं. दोनों 1957 के ही बैच के हैं. लेकिन भिंडर ने उस बैच में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था.

इसी तरह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक टी.ए. सुब्रमण्यम ने भी प्रशासनिक अधिकरण में शिकायत दर्ज करा रखी है. वे जूलियो फ्रांसिस रिबेरो के बैच के हैं. उनकी शिकायत है कि उन्हें असम गण परिषद सरकार द्वारा उनके मूल कैडर से हटा दिए जाने के बाद केंद्र ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया.

पुलिस अधिकारियों की शिकायतों का राग बेहद पुराना है जो आईएएस के प्रभुत्व का रोना रोने से शुरू होता है. गृह मंत्रालय

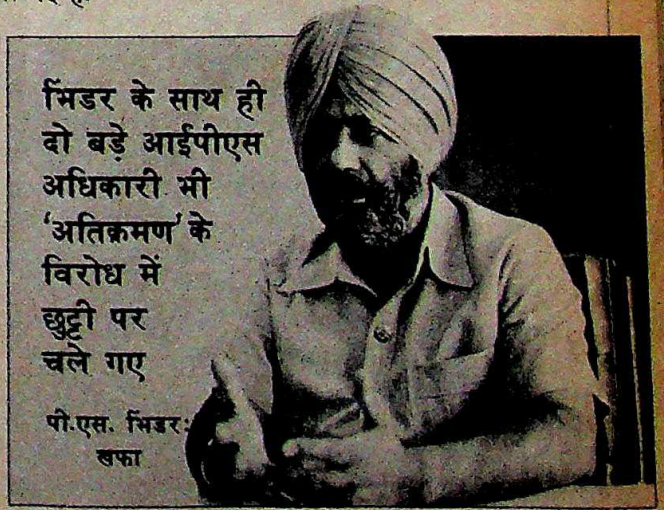

भिंडर के साथ ही दो बड़े आईपीएस अधिकारी भी 'अतिक्रमण' के विरोध में छुट्टी पर चले गए

पी.एस. भिंडर: खफा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वारा 'प्रांतीय पक्षपात' बरतने की शिकायतें भी की जाती हैं. मसलन पिछले दिनों वरिष्ठता क्रम लांघने वाले अमूमन सभी अधिकारी विंध्य के दक्षिणी हिस्से के हैं. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता इस आरोप पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं. "जरा यह भी तो देखिए, शिकायत कौन कर रहा है," ये वही भिडर हैं जो अपने स्वर्णिम दौर में दूसरों की वरिष्ठता को लांघकर ऊपर पहुंच गए थे.

एक और अहम मसले पर आईपीएस अधिकारी आईएएस वालों से लगभग हारी हुई जंग लड़ रहे हैं. विवाद का मुद्दा है पुलिस अधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण सालाना गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) कौन लिखे. कई राज्यों ने इसका अधिकार अब गृह आयुक्तों को सौंप दिया हैं. आईपीएस अधिकारी संघ के सचिव गौतम कौल कहते हैं, "इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत व्यवस्था दिए जाने के बावजूद यह कार्रवाई की गई."

पुलिसवालों का कहना है कि जब हालात बिगड़ जाते हैं तो सरकार आईएएस को दरकिनार कर पुलिस को जिम्मेदारी सौंपना पसंद करती है. रिबेरो और के.पी.एस. गिल का मामला इसका सबूत है. अथवा रमेश हांडा को ही लें जो अशांत दार्जिलिंग की बागडोर संभाले हुए हैं. उस अधिकारी का कहना है, "बेहद दुरूह परिस्थितियों में मोर्चा संभालने का जिम्मा तो हम संभालें और फिर हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो, यह नहीं चल सकता."

मुख्य प्रशासनिक धारा से कटे होने के एहसास से आईपीएस संघ ने पिछले पखवाड़े अपनी अनोखी त्रैमासिक पत्रिका 'पुलिस एलर्ट' शुरू कर दी. इसके संपादक हैं गौतम कौल. इसमें राज्यों के गृह आयुक्तों को आईपीएस अधिकारियों की सालाना 'सीआर' लिखने का अधिकार देने पर दो लेख हैं. और पश्चिम बंगाल में आईएएस-आईपीएस प्रतिद्वंद्विता पर एक रिपोर्ट है. साथ ही पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए संयुक्त प्रशासनिक सेवा परीक्षा के बजाय अलग परीक्षा कराने के केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम के प्रस्ताव के विरोध में एक संयमित लेख भी है. इस मसले पर पुलिस अधिकारियों को 400 शब्दों में अपने विचार लिख भेजने की अपील की गई है. कौल कहते हैं कि उनकी पत्रिका 'केवल आईपीएस अधिकारियों के लिए' है. आईपीएस अधिकारियों की संख्या 2460 है इसलिए इसकी केवल 2,500 प्रतियां ही छापी जाती हैं.

बहरहाल, गृह मंत्रालय शायद ही पसंद करेगा कि उसके किले की कोई ईंट बगावत कर दे.

—शेखर गुप्ता

हरियाणा

कुओं में यमदूत

जहरीली गैस से कई मौतें

करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के किसान बारिश से सूखे की समाप्ति की खुशियां मना ही रहे थे कि कुओं की जहरीली गैस ने मातम का माहौल बना दिया. बरसात शुरू होने के एक पखवाड़े के भीतर ही 30 लोग मौत के मुंह में समा गए.

चार्ट: बी.के. शर्मा

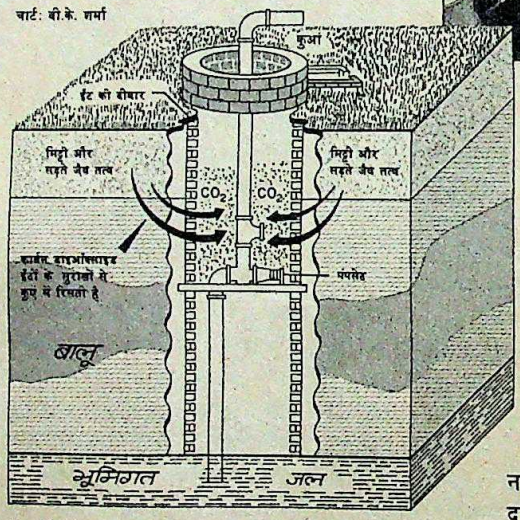

ये लोग अपने कुओं में लगे पंपसेटों को ठीक करने के लिए उतरे थे लेकिन वहां जमी जहरीली गैस ने उनका दम घोंट दिया.

जहरीली गैस के सबसे पहले शिकार होने वालों में करनाल के दराध गांव का 18 वर्षीय कुलविंदर सिंह था. 3 जुलाई को वह अपने खेत के कुएं में 20 फीट नीचे लगे पंपसेट को ढकने के लिए उतरा था. आधे घंटे बाद उसके 25 वर्षीय भाई बलविंदर और एक संबंधी मेजर सिंह ने उसे कुएं में बेहोश पड़ा देखा. बलविंदर ने सोचा कि उसके भाई को बिजली का झटका लग गया है. लिहाजा उसने बिजली काट दी और मेजर सिंह से कहा कि वे गांववालों को खबर कर दें. फिर वह खुद कुएं में उतर पड़ा. मेजर सिंह गांववालों के साथ खाट लेकर जब तक लौटे तब तक दो बच्चों के पिता बलविंदर की भी मृत्यु हो चुकी थी. तब उनके तीन संबंधियों ने मौत के कुएं में घुसने का फैसला किया. लेकिन ये लोग कमर में रस्सा बांध कर उतरे. कुएं की आधी गहराई तक जाते-

संतोष गुप्ता/हिंदुस्तान टाइम्स

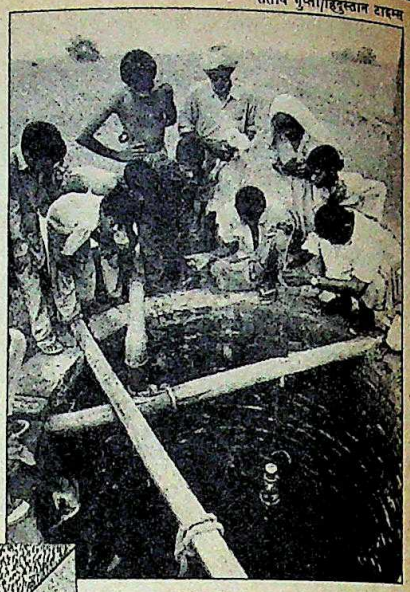

कुएं में गैस का पता लगाने के लिए लालटेन का प्रयोग

जाते तीनों बेहोश हो गए और उन्हें ऊपर खींच लिया गया.

अगले 10 दिनों के भीतर मौत की वारदात 16 दूसरे गांवों में भी हुईं. लेकिन जिला प्रशासन की नींद एक हफ्ते बाद ही टूटी. उसने गांवों में ढोल बजाकर चेतावनी दी. फिर भी लोग मरते रहे—करनाल में ही नहीं, दूसरे जिलों में भी. हरियाणा में दर्दनाक मौत की पहली वारदात के लगभग एक पखवाड़े बाद पंजाब के भटिंडा और पटियाला जिलों में इसी तरह पांच लोगों के मरने की खबर मिली.

इन मौतों से समूचे हरियाणा में आतंक फैल गया. लेकिन चंडीगढ़ में कोई हलचल नहीं हुई. राज्य के कृषिमंत्री तैय्यब हुसैन ने कहा, "ये मौतें गांववालों का निजी मामला है क्योंकि नलकूप उनकी निजी संपत्ति है." उन्होंने बड़े विचित्र तरीके से सांत्वना भी दी, "इस बार मानसून अच्छा होगा. लोग इस हादसे को जल्दी ही भूल जाएंगे."

बाद में करनाल के केंद्रीय भू-लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) और हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के वैज्ञानिकों को लेकर बनाई गई दो सरकारी समितियों ने 14 और 20 जुलाई को अपनी रिपोर्टें जारी कीं. इन वैज्ञानिकों का कहना था कि जानलेवा गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड थी जिसमें दूसरी गैसें भी मिली हुई थीं. उन्होंने गांववालों को सलाह दी कि वे कुएं में पहले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक जलता हुआ लालटेन वगैरह नीचे उतारें और अगर वह बुझ जाए तो कुएं में न उतरें. कुएं में 5 से 10 किग्रा. तक क्षारीय घोल डालें. इससे कुआं लगभग 10 मिनट तक निरापद रहेगा.

'सीएसएसआरआई' के दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों एस.के. गुप्ता और के.के. मेहता के मुताबिक सामान्यतः जैव और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से जमीन के भीतर गैस बनती है. फिर, आमतौर पर होता यह है कि बरसात होने पर बिना कोई नुकसान पहुंचाए यह फैल जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड दोनों पानी में घुलनशील हैं. लेकिन हरियाणा के इस हिस्से में दो वर्षों से बारिश नहीं हुई है, लिहाजा जमीन के भीतर बड़ी मात्रा में गैस इकट्ठा हो गई थी. जब 2 जुलाई को भारी बारिश हुई तो जानलेवा गैस से सांद्रित पानी फैल गया और गांव के बिना पलस्तर वाले लगभग 15 से 30 फुट गहरे कुओं में रिस कर चला गया. दिन में जब तापमान बढ़ा तो यह गैस पानी से अलग हो गई. चूंकि यह हवा से ज्यादा भारी होती है, इसलिए ऑक्सीजन को हटाकर खुद कुएं के तल पर फैल जाती है.

करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में भूमिगत जल स्तर में असामान्य गिरावट आ जाने के कारण किसान अपने सूखे कुओं में पंपसेट लगाने पर मजबूर हुए और उन्होंने 30 फीट या अधिक गहरी खुदाई की. इन कारणों से हादसे तो होने ही थे क्योंकि किसानों को इन पंपसेटों को ठीक करने या उन्हें ढकने के लिए कुएं में उतरना ही था, जहां सूखे कुएं में जानलेवा गैस यमदूत की तरह उनकी प्रतीक्षा कर रही थी.

केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक जल स्तर नवंबर 1986 और नवंबर 1987 के बीच छह फीट से भी नीचे चला गया था. इसकी मुख्य वजह है करनाल और कुरुक्षेत्र में बेहिसाब नलकूपों का लगाया जाना. इन जिलों के किसान दस वर्षों से मुख्यतः धान ही पैदा कर रहे हैं. इन जिलों में पिछले दशक में ही 80,000 नलकूप लगाए गए. इसके अलावा दिल्ली के लिए पीने का पानी भी करनाल से ही भेजा जाता है.

जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है. इसका अर्थ यह है कि जब भी सूखे के बाद बारिश होगी, ऐसे हादसे फिर हो सकते हैं. वैज्ञानिकों को आशंका है कि यदि जमीन से पानी निकालने पर अंकुश न लगाया गया तो कभीकभार होने वाला यह हादसा प्रायः हुआ करेगा. दुखद यह है कि एक 'असंवेदनशील सरकार अभी भी दावा करती है कि यह एक निजी त्रासदी है.

—विपुल मुद्गल

बात पते की.... कलमची

गंदी बस्ती में 'मि. क्लीन'

राजीव और सोनिया ने दिल्ली के हैजापीड़ित इलाके का दौरा किया, यह सुनकर दिल बाग-बाग हो उठा. कीचड़ और गारे के बीच सोनिया कमल जैसे झक सफेद लिबास में थीं. दूरदर्शन के लिए यह एकदम अनुकूल सीन था, मानो 'रामायण' और 'उलटा-पुलटा' को मिलाकर किसी सीरियल की शूटिंग चल रही हो. लेकिन अप्रिय भाषा में कहें तो यह खीझे लोगों को सब्जबाग दिखाने जैसा था. अफसोसनाक सच यह है कि इस पूरी कसरत को इसके सूत्रधार हरकिशनलाल भगत ने अगले चुनावों के मद्देनजर प्रचार हथकंडे के तौर पर अंजाम दिया. उन्होंने राजीव को कायल कर दिया कि रोगग्रस्त इलाकों का दौरा घाटे का सौदा नहीं होगा. प्रस्तुत है इस दौरे की झांकी:

राजीवः हद हो गई. गंदगी का आलम देखिए. ऐसा कचरा तो मैंने कभी अपने विदेशी दौरों में भी नहीं देखा. मैं 'मिस्टर क्लीन' हूं और यह सब ठीक हमारी नाक के नीचे हो रहा है. कौन है इसका जिम्मेदार?

महापौरः सर! हमने तो तीन हफ्ते पहले ही इसकी इत्तला उपराज्यपाल साहब को दे दी थी.

राजीवः कहां हैं उपराज्यपाल?

उपराज्यपालः सर! महापौर के दफ्तर ने मुझे भरोसा दिलाया था कि हर संभव कार्रवाई की जा रही है.

अनजान दर्शकः जनाब! हुआ-हुआया कुछ नहीं. इलाके में भगत जी के दौर के बाद ही काम शुरू हुआ.

उपराज्यपाल और महापौर (समवेत स्वर में): सारा कसूर नगर निगम का है.

राजीव (गरजते हुए): कहां हैं नगर निगम वाले?

निगम पार्षद (कांपते हुए): सर! हम तो पिछले तीन हफ्तों से काम कर रहे हैं.

राजीवः और उससे पहले तीन हफ्ते आप कहां सोए थे?

निगम पार्षद (असहाय होकर): उस वक्त तो कोई समस्या नहीं थी, सर! मानसून शुरू ही नहीं हुआ था.

अनजान दर्शकः जनाब! चिंता तो सिर्फ भगत जी को थी. वो तो तीन महीने पहले से ही हमारी खैरियत पूछते आए थे.

उपराज्यपाल, महापौर और निगम पार्षद (समवेत स्वर में): सारा कसूर डीडीए का है, सर! उसने आवास की उचित सुविधाएं ही मुहैया नहीं करवाईं.

राजीवः कहां हैं ये डीडीए वाले?

डीडीए अधिकारीः हां सर, नहीं सर! हमारे पास हरेक के वास्ते मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है.

दूरदर्शन कैमरामैन (भगत से फुसफुसाते हुए): सर! आप थोड़ा आगे सरकिए, सोनिया जी का साया आप पर पड़ रहा है.

राजीवः क्यों? पैसा क्यों नहीं है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

अनजान दर्शकः भगत जी की जनाब! वे ही हमें पैसा देते आए हैं अ-र-र- मेरा मतलब है वे हमारे लिए चिंतित रहते हैं...

राजीवः हां-हां, ठीक है. पर इस सारी गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है?

उपराज्यपाल, महापौर, निगम पार्षद, डीडीए अधिकारी (समवेत स्वर में): केंद्र, सर! अगर वह हमें ज्यादा पैसा दे, तभी हम बेहतर काम कर सकते हैं.

राजीव (अब तक आग-बबूला हो चुके): केंद्र? वह तो खूब पैसा बहा रहा है. पर केंद्र है कहां?

कार्टून: बजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जम्मू-कश्मीर

चुराई हुई जीत

धांधली की परंपरा निभाई गई

चुनावों में धांधली यहां अक्सर व्यापक पैमाने पर होती आई है. इसलिए हाल के उधमपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस और इंका के गठजोड़ पर जब धांधली के आरोप लगने लगे तो किसी को कोई हैरानी नहीं हुई. पर जल्दी ही इंका के खिलाफ आरोप इतने मुखर हो उठे कि चुनाव आयोग भी सुनकर उलझन में पड़ गया.

धांधली और मतदान केंद्रों पर कब्जे के शुरुआती आरोप तो 18 जून को ही दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में पहुंचने लगे थे जबकि अभी मतगणना शुरू भी नहीं हुई थी. पर मतगणना का रुख साझा विपक्षी उम्मीदवार और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह के खिलाफ एकाएक पलट जाने से इन आरोपों को बल मिला. 15 में से 12 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती पूरी होने तक वे अपने प्रतिद्वंद्वी इंका के मुहम्मद अयूब खां से 33,000 वोटों से आगे चल रहे थे. लेकिन जब दूरदराज के पहाड़ी इलाकों के बाकी तीन हलकों की गिनती शुरू हुई तो उनकी बढ़त घटने लगी.

यह देखकर भीम सिंह और विपक्षी नेता बेइमानी के आरोप लगाने लगे. मतदान के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने साबित किया कि बनिहाल, गुलाबगढ़ और रामनगर के 10 मतदान केंद्रों पर 'असामान्य मतदान' हुआ था जो कि चुनाव आयोग के नियमानुसार अमान्य है. इन केंद्रों पर 90 फीसदी वोट पड़े थे (जबकि औसत मतदान 40 फीसदी था) और इनमें भी 81 फीसदी इंका के खाते में गए थे. यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के सूत्रों ने भी निजी बातचीत में माना कि इससे मतदान केंद्रों पर कब्जे की आशंका सही साबित होती है. सबूत मिलने पर आयोग ने इन सभी 10 केंद्रों के अलावा चार दूसरे केंद्रों में, जहां मतपेटियों में हेराफेरी की गई थी, दुबारा मतदान कराने का आदेश दिया.

लेकिन इससे मामला सुलझा नहीं. भीम सिंह ने आरोप लगाया कि पुनर्मतदान में भी जबरदस्त धांधली हुई है. इसमें वे 2376 वोटों से हार गए. उन्होंने कहा, "स्थानीय प्रशासन ने ऐसा बरताव किया मानो वह इंका का दलाल हो."

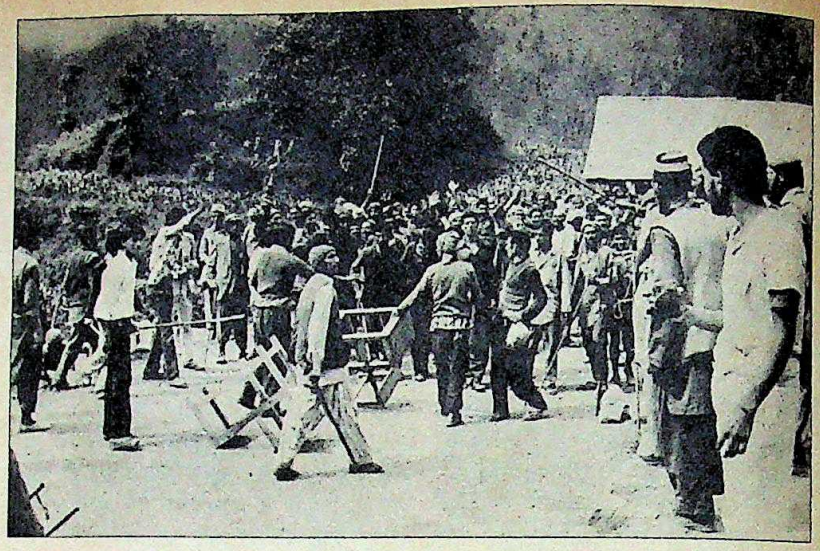

प्रमोद पुष्करणा

गुलाबगढ़ मतदान केंद्र पर तनाव; और (नीचे) चुनाव आयुक्त के दफ्तर के बाहर भीम सिंह

पैंथर्स पार्टी और विपक्ष द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप, जिनमें से कइयों के सबूत के रूप में फोटो और व्यक्तिगत गवाहियां भी हैं, इस प्रकार हैं:

- सत्ताधारी इंका-नेशनल कान्फ्रेंस गठबंधन ने गुंडों की भीड़ जुटा रखी थी ताकि खनेड, खौड़ और गुलाबगढ़ में बलवे कराने के बाद मतदान केंद्रों पर कब्जे किए जा सकें.
- चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए केंद्रीय पुलिसवालों को मतदान केंद्रों पर तैनात नहीं किया गया.
- कई स्थानों पर भीड़ ने पैंथर्स पार्टी के एजेंटों को खदेड़ दिया. मौका-ए-वारदात की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया.
- मतदान केंद्रों पर कब्जा करने में स्थानीय प्रशासन की सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीभगत थी और उसने भीम सिंह के चुनाव एजेंटों को मतपेटियों के साथ नहीं जाने दिया.
- आयोग के पर्यवेक्षक जी.डी. शर्मा की रिपोर्ट दाखिल हुए बगैर ही चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी गई.
- धांधली के गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग ने जांच कराने की मांग साफ नामंजूर कर दी.

लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त आर.वी.एस. पेरीशास्त्री कहते हैं, "हमने चुनाव नियम-कायदों के मुताबिक कराया. मतदान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा दाखिल रिपोर्टों के मद्देनजर ही हमने परिणाम की घोषणा की है."

लेकिन इस खंडन से ही उधमपुर के मतदाताओं की आहत भावनाओं पर मरहम नहीं लगाया जा सकता. वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. भीम सिंह का यह आरोप कि सरकार ने उनके पक्ष में पड़े वोटों को 'चुरा' लिया, गंभीर मामला है. चुनाव धांधली लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महंगी पड़ती है क्योंकि इससे व्यवस्था के प्रति जनता के मन में दुराव बढ़ता है. भीम सिंह कहते हैं, "जब चुनाव से लोगों का भरोसा उठ जाता है तो वे हिंसा का रास्ता ही पकड़ते हैं." उधर कश्मीर घाटी में लोग पहले से ही भड़के हुए हैं इसलिए जम्मू में भी हिंसा की भावना भड़काना सरकार के हित में नहीं हो सकता. —पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्व-प्रसिद्ध शृंखला

पुस्तक महल की 30 पुस्तकों का
एक अनूठा प्रोजेक्ट

मूल्य: 15/- प्रत्येक
डाकखर्च: 4/- प्रत्येक
एक साथ चार पुस्तकें मंगाने पर डाकखर्च माफ

- प्रामाणिक शोध-सामग्री
- प्रत्येक पुस्तक सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित
- सरस कथा शैली
- बढ़िया कागज पर ऑफसैट छपाई
- बहुरंगी आवरण
- बाइंडिंग क्लाथ

इस शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय जगत से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करना है।

कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को पूर्ण रूप से उजागर करने वाला एक सचित्र **'मिनि एनसाइक्लोपीडिया'** है।

उदाहरणार्थ 'रोमांचक कारनामे' में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो 'खोजें' में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। 'अनसुलझे रहस्य' में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर भूत-प्रेतों तथा रक्त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो 'खेल और खिलाड़ी' व 'वैज्ञानिक' क्रमशः जीवनी प्रधान पुस्तकें हैं। 'विनाश-लीलाएं' में प्रकृति के प्रलयंकारी रूप का चित्रण है तो 'दुर्घटनाएं' में मानवीय भूलों से हुई मर्मांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है। 'गुप्तचर संस्थाएं' तथा 'जासूस' में मकड़े के जालों सी फैली जासूसी संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं तो 'प्रेरक-प्रसंग' किसी भी जहाज की तरह भटके हुए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ है।

इस शृंखला में प्रकाशित पुस्तकें:

विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल एवं खिलाड़ी 8. रिकॉर्ड्स-I 9. रिकॉर्ड्स-II 10. वैज्ञानिक 11. विनाश - लीलाएं 12. दुर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं 14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग 16. चिकित्सा-पद्धतियां 17. जासूसी-कांड।

तैयारी में/प्रेस में:—

- बैंक-डकैतियां
- क्रूर हत्यारे
- सभ्यताएं
- खजाने
- राजनैतिक हत्याएं
- खोजी-यात्राएं
- स्कैण्डल।

आमंत्रण:—

प्रोजक्ट में योगदान के लिए विद्वान लेखक तथा अनुवादक संपर्क साधें।

अपने निकट के बुकस्टॉल एवं रेलवे तथा बस अड्डों पर स्थित बुकस्टॉलों पर मांग करें अन्यथा वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता:—

पुस्तक महल, खारी बावली, दिल्ली-110006

शो रूम: 10-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

ब्रांच ऑफिस: 22/2 मिशन रोड (शामा राव कम्पाउंड), बंगलौर-560027

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

अनूठी सरकारी दानशीलता

शराब व्यापारी द्वारा भूमि कानूनों की अवहेलना की अनदेखी

शराब और राजनीति का मेल उतना ही शानदार होता है जितना शराब और सोडे का. इसकी जीती-जागती मिसाल है मद्रास के बाहरी इलाके पोरूर में 259.35 एकड़ के विशाल परिसर में बना 'श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट'. शराब के बड़े व्यापारी रामास्वामी उदयार के श्रीरामचंद्र मेडिकल ट्रस्ट ने 125.66 एकड़ सरकारी जमीन पर इस कॉलेज का निर्माण कर रखा है. मगर किसकी मजाल जो कोई सवाल खड़ा कर सके. बल्कि राष्ट्रपति शासन के तहत काम कर रहा तमिलनाडु प्रशासन तो पिछले पखवाड़े यह जमीन ट्रस्ट को दान में देने के उपाय तलाश रहा था. राजनैतिक दबाव के कारण इस तरह की सरकारी दानशीलता कोई नई बात नहीं है. ट्रस्ट को पहले ही भूमि कानूनों के संदर्भ में छूट दी जा चुकी है.

इसलिए यदि राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर का प्रशासन ट्रस्ट की मदद करने की कोशिश कर रहा है तो वह दिवंगत मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन द्वारा स्थापित परंपरा ही निभा रहा है. लेकिन इस प्रक्रिया में अलेक्जेंडर का यह दावा झूठा साबित हो रहा है कि वे राज्य को साफ-सुथरा प्रशासन दे रहे हैं.

एमजीआर के करीबी रहे उदयार पांच साल पहले इस नौ-सदस्यीय ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी बने. इसके तुरंत बाद ही यह कॉलेज मद्रास के उत्तर-पश्चिम में एक भवन में चलाया जाने लगा. पोरूर में कॉलेज की आधारशिला 11 सितंबर 1985 को खुद एमजीआर ने ही रखी थी और ट्रस्ट ने जो सरकारी जमीन हथियाई वह वैध हो गई. लेकिन पूर्व वित्तमंत्री वी.आर नेदुनचेडियन ने 12 सितंबर 1986 को फाइलों में दर्ज किया था कि ट्रस्ट को उस जमीन पर इमारतें बनाने का अधिकार तो नहीं ही है, उस क्षेत्र में घुसने तक का अधिकार भी नहीं है.

लेकिन जब एमजीआर का वरदहस्त सिर पर था तो इस संस्था के लिए कोई भी बाधा विकट कैसे हो जाती. फिलहाल 35 एकड़ पर कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास और कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए हैं. ये सभी इमारतें सरकारी जमीन पर ही बनी हुई हैं. ट्रस्ट के कब्जे वाली बाकी 133.69 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों को आबंटित कर रखी है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि संस्थान जमीन के इस हिस्से पर कैसे काबिज है.

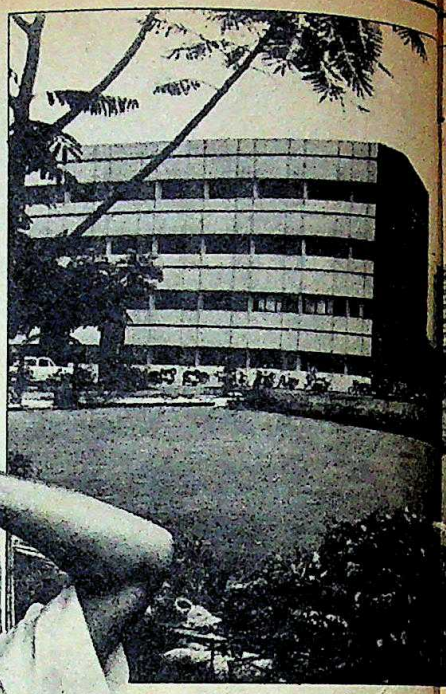

श्याम टेकवानी

रामास्वामी उदयार; और (ऊपर) कॉलेज व अस्पताल: खुल्लमखुल्ला ज्यादती

इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने जमीन की मिल्कियत की परवाह तो नहीं ही की, उस पर इमारतें बनाने के लिए मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमडीए) से मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं समझी. मामला एमएमडीए के पास जाता तो वह जमीन की मिल्कियत या कम-से-कम उसके पट्टे के अधिकारपत्र के बगैर निर्माण की मंजूरी नहीं देता. नाम न छापने की शर्त पर तमिलनाडु के एक सरकारी अफसर ने कहा, "तकनीकी तौर पर देखें तो उदयार और दूसरे न्यासियों ने जमीन पर बेजा कब्जा किया है. अब एमएमडीए द्वारा उचित कार्रवाई तो यही होगी कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करे और इमारतों को गिरवा दे." लेकिन एमएमडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

उधर ट्रस्ट का काम मजे से चल रहा है. कॉलेज में अब तक 500 छात्र दाखिला ले चुके हैं और पहला बैच तो एमबीबीएस के पांच साल के कोर्स के अंतिम वर्ष में पहुंच चुका है. अस्पताल में मंजूरशुदा 1,000 बिस्तरों में से 350 बिस्तर इस साल फरवरी तक लग गए. ट्रस्ट के सचिव की हैसियत से कॉलेज की देखरेख करने वाली, उदयार की पुत्रवधू राधा वेंकटचलम कहती हैं, "उम्मीद है कि बाकी 650 बिस्तर भी इस साल के अंत तक लग जाएंगे." वे यह भी बताती हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

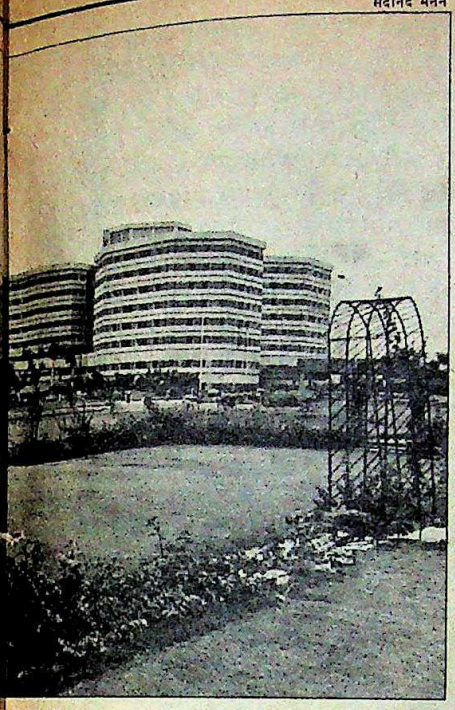
सदानंद मेनन

बेजा कब्जे की कहानी

1986

सितंबर नेदुनचेडियन फाइलों में जमीन पर बेजा कब्जे का नोट लगाते हैं.

1987

जनवरी आदेश सं. 41 पारित: सरकारी जलाशयों को बेचने या पट्टे पर देने पर रोक.

अप्रैल धर्मार्थ संगठनों की जमीन की हदबंदी बढ़ाने के लिए शहरी जमीन हदबंदी कानून में संशोधन जिससे उदयार को लाभ.

जुलाई सरकारी चरागाह को बेचने या पट्टे पर देने पर प्रतिबंध.

दिसंबर आदेश सं. 1959 पारित: कॉलिज को 259.35 एकड़ जमीन रखने की अनुमति. उदयार के मुख्य संरक्षक एमजीआर की मृत्यु.

1988

जनवरी राष्ट्रपति शासन. समस्याएं बढ़ीं.

मई जमीन की पूरी तरह से बिक्री के लिए उदयार का सरकार को पत्र.

जून कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव पर विचार करती है.
कलेक्टर 32,200 रु. एकड़ की दर से जमीन की कीमत आंकते हैं.
राजस्व विभाग जमीन पूरी तरह से बेचने की सिफारिश करता है.
भू-प्रशासन आयुक्त श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज को पट्टे पर जमीन देने की सिफारिश करते हैं. यह नोट भी लगाते हैं कि जमीन के बाजार मूल्य का उनका मूल्यांकन 2.08 करोड़ रु. है. वे पट्टे के सालाना किराए के रूप में इसके 10 फीसदी की सिफारिश करते हैं.

कि अस्पताल में हर रोज 1100 से अधिक बाह्य रोगियों का इलाज किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस परियोजना में ट्रस्ट करीब 30 करोड़ रु. खर्च कर चुका है.

अस्पताल को औपचारिक मान्यता भी जल्दी ही मिलने वाली है. इस संस्थान को अस्थायी मान्यता प्रदान करने से पहले जांच के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (भाचिप) के निरीक्षकों का एक दल पिछले पखवाड़े पोरूर गया था. स्थायी मान्यता छात्रों के पहले बैच द्वारा पांच साल का कोर्स पूरा करने के बाद ही मिल सकती है. भाचिप को प्रभावित करने में संस्थान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि पहले से ही इसके पास चिकित्सा के अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं. इनके अलावा वह कुछ खास तरह के संक्रामक रोगों के जल्दी निदान के लिए 'न्यूक्लीयर मैग्नेटिक रेजोनेंस' उपकरण भी आयात करने जा रहा है.

एक तरफ तो संस्थान अपनी योजनाओं पर अमल करता जा रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार कुछ कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है. राज्य के शहरी भूमि हदबंदी कानून के मुताबिक श्री रामचंद्र ट्रस्ट जैसी कोई भी संस्था इतनी ज्यादा जमीन की मालिक नहीं हो सकती. वैसे यह बात और है कि ट्रस्ट उस जमीन का वैध मालिक नहीं है. इसलिए अप्रैल 1987 में सरकार ने भूमि कानून में संशोधन किया और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए हदबंदी बढ़ा दी गई. यह ट्रस्ट भी धर्मार्थ संस्था होने का दावा कर सकता है क्योंकि इसके अस्पताल में बिस्तरों की कुल संख्या का एक-तिहाई गरीबों के लिए मुफ्त रखने की उम्मीद है. और तो और, राजस्व विभाग ने पिछले साल 12 दिसंबर को एक दूसरा आदेश (संख्या: 1959) जारी किया. इसके तहत संस्थान 259.35 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा रख सकता है.

लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद असली समस्या बनी ही रहती है कि वह जमीन सरकारी ही रहेगी. इसके बाद ट्रस्ट पर गाज यह गिरी कि एमजीआर की मृत्यु हो गई और 12 दिसंबर को सरकारी आदेश के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया. राज्य के कुछ उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसके बाद उदयार ने दिल्ली के इंकाई नेताओं को पटाना शुरू कर दिया. 31 मई को उदयार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी कि जमीन ट्रस्ट के हाथ बेच दी जाए. अधिकारियों का आरोप है कि इस प्रस्ताव पर विचार करने वास्ते प्रशासनिक समिति की जल्दी बैठक बुलाने के लिए केंद्र की शह पर राज्य सरकार पर दबाव डाला गया. समिति के सदस्य राज्यपाल और उनके सलाहकार होते हैं और सभी बड़े फैसले यही समिति लेती है. इसकी बैठक मई में हुई और इस प्रस्ताव पर विचार किया गया. समिति ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी. बताया जाता है कि अभी पिछले पखवाड़े तक राज्यपाल के मुख्य सलाहकार रहे डॉ. एस.एस. सिद्धू ने राजस्व विभाग से कहा कि वह उदयार को जमीन बेचने संबंधित फाइल तैयार करे. अब यह फाइल समिति के विचाराधीन है. अंतिम फैसला बाकी है.

यदि यहां से हरी झंडी मिल जाती है तो उदयार के लिए अगली मुश्किल होगी सरकार द्वारा जमीन की कीमत की मांग. भीतरी सूत्रों का कहना है कि भू-प्रशासन आयुक्त वी. राममूर्ति ने जमीन की कीमत 2 लाख रु. प्रति एकड़ आंकी है और उन्होंने सुझाया है कि कुल कीमत के दसमांश के बराबर सालाना किराये पर जमीन ट्रस्ट को पट्टे पर दी जाए. इस तरह जमीन का सालाना किराया करीब 20.8 लाख रु. पड़ेगा. मद्रास के कलेक्टर ने पोरूर में चल रही बाजार दर 9 लाख रु. प्रति एकड़ के मुकाबले उस जमीन की कीमत 32,200 रु. प्रति एकड़ लगाई है.

बहरहाल, जमीन की कीमत का मामला सुलझाने से पहले राजस्व विभाग को अपनी घोषित नीतियों के घेरे से निकलने का रास्ता ढूंढ़ना होगा. विभाग ने पिछले साल 20 जनवरी को एक आदेश (संख्या: 41) जारी कर जल मार्ग के किनारे की सरकारी जमीन की बिक्री, उसे पट्टे या अनुदान में देने पर विशेष प्रतिबंध लगा दिया. बाद में इस प्रतिबंध के दायरे में चरागाहों को भी शामिल कर लिया गया. उदयार अपने ट्रस्ट के लिए जो जमीन चाहते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा जल मार्ग के किनारे का है और बाकी चरागाह का है. राजभवन के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक राजस्व विभाग ने अब इस प्रतिबंध को उदार बनाने की सिफारिश की है. बताया जाता है कि भू-प्रशासन आयुक्त द्वारा जमीन को पट्टे पर देने की सिफारिश के बावजूद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्व विभाग ने दिल्ली के दबाव में आकर 32,200 रु. प्रति एकड़ की दर से जमीन उदयार को बेचने की सिफारिश की है.

लेकिन एक ओर सरकार जहां उदयार के प्रति इतनी उदारता बरतने को तैयार है, वहीं वह द्रविड कडगम के अध्यक्ष के. वीरमणि को कोई रियायत देने को तैयार नहीं दिखती. तंजावुर जिले के वल्लम में वे राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं. वीरमणि अपने कॉलेज के लिए 40 एकड़ जमीन खरीदना चाहते हैं पर सरकार सिर्फ पट्टे पर जमीन देने को राजी है. सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक पट्टे का सालाना किराया जमीन की कीमत का दस प्रतिशत होगा.

इसी तरह मद्रास सेंट्रल स्टेशन के पास पुराने प्राणि उद्यान क्षेत्र को भी व्यापारिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल यह इलाका मनोरंजन स्थल के रूप में वर्गीकृत है. जनअसंतोष को अनदेखा करके पर्यटन सचिव अशोक जोशी ने इस इलाके के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश की है ताकि यहां एक पांच सितारा होटल बनाया जा सके.

इस होटल के निर्माण का प्रस्ताव संयुक्त क्षेत्र के पल्लव होटल्स कार्पोरेशन लि. की तरफ से आया है. इस कंपनी में तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम और डॉ. पी.जी पेरियास्वामी की अगुआई में अमेरिका के अप्रवासी भारतीयों का एक दल शामिल है. पेरियास्वामी भी एमजीआर के करीबी थे और अब उदयार की तरह उन्होंने भी इंका से सांठगांठ कर ली है. स्थानीय लोग इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस 18 एकड़ जमीन पर होटल बनाने की बात है उसके एक-तिहाई हिस्से पर एक प्राकृतिक झील, पेड़-पौधे तथा झाड़ियां हैं.

प्रस्ताव के मुताबिक झील वाले हिस्से की सात एकड़ जमीन होटल्स निगम को इस शर्त पर दी जाएगी कि वह झील को दुरुस्त रखेगा. बाकी जमीन 22.25 लाख रु. प्रति एकड़ की दर से बेची जाएगी. हालांकि पड़ोस में ही जमीन की कीमत प्रति एकड़ 2.70 से 3.60 करोड़ रु. के बीच है. हैरतअंगेज बात तो यह है कि पेरियास्वामी संयुक्त क्षेत्र की इस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों हैं जबकि संयुक्त क्षेत्र की कंपनी में अध्यक्ष पद पर कोई सरकारी प्रतिनिधि होना चाहिए जिसे मत डालने का अधिकार हो.

बहरहाल, स्थिति यह है कि अब जबकि एमजीआर सरकार के गड़े मुर्दे कब्रों से निकलकर बदबू फैलाने लगे हैं, राज्यपाल अलेक्जेंडर के प्रशासन की करतूतें भी उसमें इजाफा ही कर रही हैं. —एस.एच. वेंकटरमनी

तमिलनाडु

बंटे हुए फिर बंटे

जयललिता गुट में गहरी फूट

तमिलनाडु के राजनैतिक तमाशे में पिछले पखवाड़े एक और नाटकीय मोड़ आया. वहां की राजनीति की एक प्रमुख नायिका जयललिता जयराम के कुछ 'सहयोगी कलाकार' उनका साथ छोड़ गए. अन्नाद्रमुक के जयललिता गुट में उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वालों में पूर्व वित्तमंत्री वी.आर. नेदुनचेडियन, अन्नाद्रमुक (जयललिता) के पूर्व उप-महासचिव एस. रामचंद्रन और जयललिता की पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष एस. तिरुनावक्करसु शामिल हैं. ये सभी जयललिता के तानाशाही अंदाज और पार्टी कोष के तथाकथित दुरुपयोग के कारण नाराज हैं.

(ऊपर) नेदुनचेडियन; (नीचे) रामचंद्रन; और (दाएं) जयललिता

यह गुट अभी औपचारिक रूप से बंटा नहीं है लेकिन इसमें अब ज्यादा देर भी नहीं. एस. रामचंद्रन भी कहते हैं, "अभी तक हम औपचारिक रूप से तो बंटे नहीं हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से हम अलग हो गए हैं."

जयललिता गुट की प्रतिक्रिया भी ऐसी ही थी. पार्टी के प्रचार सचिव के.के. एस.एस.आर. रामचंद्रन ने कहा, "चूंकि असंतुष्टों ने अपने आपको अलग गुट घोषित कर ही दिया है इसलिए अब उनसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं."

लेकिन लगता है कि असंतुष्ट नेताओं ने अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही अनुमान लगा लिया था क्योंकि पार्टी के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता जयललिता के साथ ही बने हुए हैं. अब सवाल यह है कि नेदुनचेडियन और उनके साथी किसके समर्थन की आस में हैं. तिरुनावक्करसु के अनुसार उनका गुट अब जानकी गुट के साथ मेल की कोशिश करेगा क्योंकि जयललिता दोनों ही की दुश्मन हैं.

जानकी गुट के अधिकांश नेता भी असंतुष्टों को अपने साथ ले लेने के पक्ष में हैं लेकिन इस गुट के ताकतवर नेता आर.एम. वीरप्पन और उनके समर्थक भविष्य में हो सकने वाले अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति कुछ शंकालु हैं. इतना ही नहीं, कट्टर द्रविड वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वे इंका की जगह द्रमुक के साथ चुनावी गठबंधन के पक्ष में हैं. जानकी अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए अमेरिका गई हुई हैं इसलिए यह मालूम नहीं हो सका कि वे अपने 'परम विरोधी' खेमे से आए लोगों का स्वागत करेंगी या नहीं.

जहां तक इंका की बात है, उसे अन्नाद्रमुक मे फूट पड़ते जाने से लाभ ही होगा क्योंकि तब वह उनसे समझौता करने की बेहतर स्थिति में होगी. अगर विभिन्न गुटों की लड़ाई नहीं थमी तो इंका को चुनाव में भी फायदा मिलेगा. लेकिन इंका अन्नाद्रमुक के किस धड़े से गठबंधन करे इस बात का निर्णय न हो पाने से पार्टी में संभ्रम बढ़ता जा रहा है. तमिलनाडु प्रदेश इंका के उपाध्यक्ष एस.आर. बालसुब्रमण्यम ने कहा, "हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि जनता किस धड़े को अपना मानती है और कौन अपने को एमजीआर का असली वारिस साबित करता है. सब कुछ फिलहाल अनिश्चित ही है."

पिछले पखवाड़े के घटनाक्रम के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि आपसी कलह से अन्नाद्रमुक के लोग एमजीआर की मिट्टी पलीद कर रहे हैं. — एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation

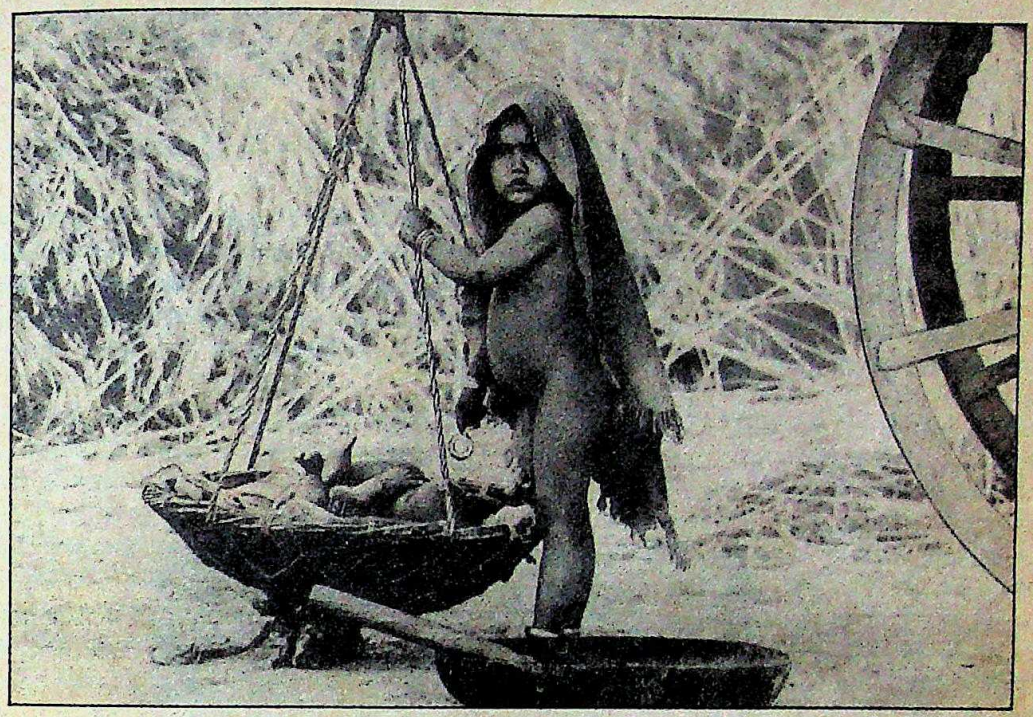

तस्वीर यूनिसेफ के सौजन्य से

एक मीटर कपड़ा खरीदने के लिए बहुत कम पैसे की ज़रूरत है। पर ज़रा कल्पना कीजिए, 200 करोड़ मीटर कपड़े के मूल्य की। हम और आप मिलकर इस पैसे को बरबाद कर रहे हैं। हर साल।

दुख की बात तो यह है कि इतना बड़ा सच हमें छूता तक नहीं। कहीं चुभता भी नहीं। क्योंकि हमारे पास कई ज़रूरी चीज़ें हैं सोचने को-करने को। ऐसी फ़ालतू बातों के लिए भला समय कहाँ? हमारी आँखों पर बंधी लापरवाही की पट्टी हमें कुछ देखने नहीं देती।

2000 करोड़ रु० की बरबादी हर साल हो रही है और ये हम सब मिलकर कर रहे हैं।

सड़कों पर, रसोई घरों में, कारखानों और खेतों में। हर जगह, हर कहीं होती है पेट्रोलियम की बरबादी। क्योंकि ज़्यादा ईंधन खाने वाले पुराने डिज़ाइन के उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं। सवारी की सही देखभाल नहीं होती। और न ही हमारी आदतों और ड्राईविंग के तरीकों में सुधार।

आपके ज़रा से जागरुक प्रयास से इस फ़ज़ूलखर्ची को रोका जा सकता है। लोगों की सोई हुई चेतना को जगाया जा सकता है। बिखरी हुई आवाज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत बरबादी हो चुकी। अब और नहीं। आइए, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठायें। अपने अखबारों में लिखें। अपनी कॉलोनी, ऑफिस, क्लबों, संस्थाओं—हर तरफ चर्चा करें। काम करने वाले लोगों की सक्रिय टोलियाँ बनायें।

आपकी मदद के बिना कुछ नहीं हो पायेगा। पेट्रोलियम बचाने का संदेश घर-घर तक आपको ही पहुँचाना है।

हम आशा करते हैं कि आप चुप रहने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस पन्ने को पलट कर कहेंगे—

"मेरी बला से!"

इस विषय पर आइए हमसे मिलिए। आपके विचारों का स्वागत है।

पेट्रोलियम कंज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन

1008, नई दिल्ली हाऊस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन 9310006, 9319066

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

HTA 5373 HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वायुदूत

एलान से आया तूफान

भारत को 'कासा' विमान बेचने की स्पेनी कोशिश से नया बावेला

पिछले पखवाड़े प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्पेन यात्रा के दौरान एक धमाकेदार एलान हुआ कि भारत वायुदूत के लिए 'कासा' विमान खरीदेगा. 'कासा' ने वायुदूत के लिए अपने दो विमान मैदान में उतारे थे. इनमें से एक तो चार साल पहले ही नामंजूर कर दिया गया जबकि दूसरे को अभी हाल में वायुदूत द्वारा विचार के लिए चयनित चार विमानों की छोटी-सी सूची में भी जगह नहीं मिली. इस परिदृश्य में स्पेनी विमान के अचानक आ टपकने से नए विवाद का सूत्रपात हो गया है. यह रिपोर्ट लिखने के लिए विशेष संवाददाता रमिंदर सिंह ने नई दिल्ली में उड्डयन सूत्रों को टटोला तो जॉजिना हाइगेरास ने मैड्रिड में अधिकारियों से बात की.

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पिछले दिनों चार देशों का तूफानी दौरा किया. इन देशों में जॉर्डन, तुर्की, युगोस्लाविया के अलावा स्पेन भी शामिल था. स्पेन के दौरे से भूमध्यसागर में कोई तूफान नहीं आया पर भारत में खासा हंगामा खड़ा हो गया. इसकी वजह यह घोषणा थी कि स्पेन भारत को सहायक एअर-लाइन वायुदूत के लिए 'कासा' विमान देगा. दौरे की समाप्ति पर मैड्रिड में हुए संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में स्पेनी प्रधानमंत्री फेलिप गोंजालेज ने जब यह घोषणा की कि भारत चार 'कासा' विमान खरीदने के लिए सहमत हो गया है तब राजीव के होंठों पर मुस्कान तैर रही थी.

■ पत्रकार सम्मेलन में स्पेनी प्रधानमंत्री गोंजालेज के साथ राजीव

स्पेनी राजदूत कार्लोस फर्नांडीस एस्पेसो, जो उस समय मैड्रिड में ही मौजूद थे, कहते हैं, "यह तो अनौपचारिक टिप्पणी थी, कोई घोषणा नहीं." टिप्पणी अनौपचारिक थी या नहीं पर 'कासा' विमानों का जिक्र आते ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय एकबारगी ठगा-सा रह गया. उसने प्रमुख वायुमार्गों पर चल रहे वायुदूत के पुराने टर्बोप्रॉप्स की जगह नए विमानों के चयन की योजना बड़ी मशक्कत से तैयार कर रखी थी. करीब दो साल तक सभी उपयुक्त विमानों की जांच-परख के बाद एक उच्चस्तरीय आकलन समिति इस नतीजे पर पहुंची थी कि सीएन-235 विमान विचार करने लायक नहीं हैं.

राजीव गांधी अभी एअर इंडिया के विशेष विमान 'गोमती' से देश लौट ही रहे थे कि वायुदूत की आकलन समिति हरकत में आ गई. 15 महीने से अलमारियों में धूल चाट रही 'कासा' के प्रस्तावों की फ़ाइल को झाड़-पोंछकर फिर समिति के सदस्यों के सामने रख दिया गया. समिति अपनी रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपने ही वाली थी. पर उसने यह काम एक हफ्ते के लिए मुल्तवी कर दिया ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बात की आधिकारिक जानकारी मिल जाए कि 44 सीटों वाले स्पेनी विमान की खरीद में राजीव की कितनी दिलचस्पी है. पिछले साल वायुदूत को यह विमान करीब 75 लाख डॉलर (10 करोड़) में देने का प्रस्ताव था.

'इंडिया टुडे' द्वारा मैड्रिड में की गई पड़ताल से पता चला कि स्पेनी प्रधानमंत्री ने जिस विमान का जिक्र किया था वह दरअसल सीएन-235 नहीं बल्कि 25 सीटों वाला सी-212 है. 'कासा' अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि कुछ सी-212 विमानों की बिक्री के मामले में भारत सरकार से 'शुरुआती बातचीत' हुई थी. उसके प्रवक्ता के अनुसार, "अभी तक चार विमान बेचने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति हुआ है." संख्या बढ़ भी सकती है. इससे रहस्य और गहरा हुआ. सी-212 उस श्रेणी का विमान है जो चार साल पहले ही होड़ से बाहर हो गया

गोंजालेज ने जब घोषणा की कि भारत 'कासा' विमान खरीदने को राजी है तो राजीव मुस्कराए पर भारत में खासा हंगामा खड़ा हो गया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था. तब चयन की लंबी प्रक्रिया के बाद सरकार ने सी-212 समेत ढेर सारे विमानों के मुकाबले 19 सीटों वाले डोर्नियर-228 को वायुदूत के लिए चुना था. और फिर हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डोर्नियर के जर्मन निर्माताओं के सहयोग से उसे भारत में ही बनाने के लिए कानपुर में कारखाना भी लगा लिया. फिर इस मामले को दुबारा क्यों उठाया गया?

इस मामले में एक सनसनीखेज तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मैड्रिड में एक स्पेनी राजनयिक जोस मारिया वाल्देमोरो भी मौजूद थे जो सोनिया गांधी की छोटी बहन के पति हैं. नई दिल्ली के स्पेनी दूतावास में कभी प्रथम सचिव रह चुके वाल्देमोरो इस समय रोम में स्पेन के सांस्कृतिक दूत हैं. राजीव के दौरे के वक्त वे छुट्टी लेकर अपनी पत्नी सहित मैड्रिड पहुंच गए थे. उन्होंने कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया जिनमें राजीव और सोनिया शामिल थे. इसमें स्पेनी प्रधानमंत्री गोंजालेज द्वारा दिया गया भोज भी शामिल था.

दौरे में वाल्देमोरो और सोनिया की बहन की मौजूदगी के बाद जब वायुदूत के लिए 'कासा' विमानों की खरीद की घोषणा हुई तो इस सौदे में 'स्पेनी संपर्कों' के जुड़े होने की अफवाहें फैल गईं. यहां तक कहा गया कि वाल्देमोरो को हाल ही में 'कासा' के निदेशक मंडल में शामिल कर लिया गया है. वाल्देमोरो गुस्से में आरोप का खंडन करते हैं, "'कासा' से मेरा संबंध उतना ही है जितना स्पेनी सरकार के किसी अधिकारी का स्पेन की किसी कंपनी से है. उन्होंने कभी मुझे किसी पद की पेशकश नहीं की और वहां नौकरी पाने में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है." 'कासा' के एक प्रवक्ता जोस मारिया सनमिलन भी कहते हैं, "हमने हमेशा भारत से सीधे बातचीत की है. जरूरत पड़ने पर अपना इंजीनियर भारत भेजते हैं. बिचौलिए की मार्फत हम नहीं जाते."

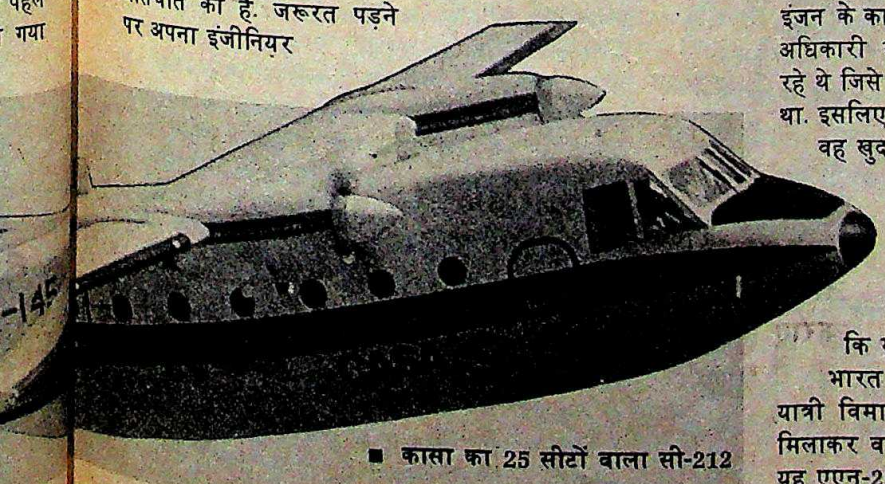

■ कासा का 25 सीटों वाला सी-212

कासा द्वारा सी-212 विमान रुपए के भुगतान पर बेचने की पेशकश से वह रूसी विमान एएन-28 का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बन गया

जाहिर है 'कासा' को पता था कि भारत से सी-212 का सौदा मुमकिन है. कुछ महीने पहले राजीव की स्पेन यात्रा की घोषणा के बाद 'कासा' का एक अधिकारी दिल्ली आया था और उसने अपने प्रस्ताव से वायुदूत के अधिकारियों को हैरत में डाल दिया था. उसका कहना था कि 'कासा' भारत को करीब 30 लाख डॉलर (चार करोड़ रु.) प्रति विमान के बराबर भारतीय रुपयों में अपना सी-212 विमान बेचने को तैयार है. उस समय वायुदूत के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे सीएन-235 जैसे किसी बड़े विमान का चुनाव करने में लगे हुए थे. इसीलिए जब उन्होंने मैड्रिड की घोषणा सुनी तो यही सोचा कि यह सीएन-235 से ही संबंधित मामला होगा. वायुदूत को उस समय यह एहसास शायद न हो लेकिन 'कासा' के प्रस्ताव से जाहिर है कि उसे वायुदूत के प्रबंधकों की योजना की पूरी जानकारी थी. डोर्नियर विमानों में इंजन के कामकाज की गड़बड़ी की वजह से निराश होकर वायुदूत के अधिकारी गंभीरता से रूसी विमान एएन-28 के बारे में सोच रहे थे जिसे एविएक्सपोर्ट ने भारतीय मुद्रा में बेचने का प्रस्ताव रखा था. इसलिए जब सी-212 को रुपए के बदले बेचने की पेशकश हुई तो वह खुद-ब-खुद एएन-28 का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बन गया.

■ रूसी विमान एएन-28

कुछ महीने पहले एक एएन-28 विमान यहां लाया गया था जिसने 64 परीक्षण उड़ाने भी भरीं. अब एक रूसी दल इसके सौदे को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली आने वाला है. करीब वैसी ही शर्तों पर सी-212 की पेशकश से सोवियत प्रस्ताव धूल भी चाट सकता है क्योंकि रूस 25 सीटों वाला एएन-28 विमान नहीं बना पाया है. भारत शुरू में चार सी-212 विमान खरीदेगा, यह घोषणा स्पेनी यात्री विमान के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है. कुल मिलाकर वायुदूत को ऐसी क्षमता वाले 20 विमानों की जरूरत है. यह एएन-28 विमान खरीदे या सी-212, एक बात तय है कि इनमें से कोई भी विमान वायुदूत में डोर्नियर के भविष्य को मिटा देगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कानपुर के एचएएल कारखाने में बनाए जाने वाले करीब 140 डोर्नियर विमानों में से 26 वायुदूत के लिए थे. उसने 10 विमान खरीदे भी पर 'डोर्नियर ऐंड गैरेट' कंपनी (डोर्नियर में लगने वाले इंजन के निर्माता) से झगड़े के बाद वायुदूत ने एचएएल को सूचित किया कि वह डोर्नियर-228 विमानों को अब स्वीकार नहीं करेगा. अगर सी-212 के साथ सौदा तय हो गया तो कानपुर में डोर्नियर-228 के उत्पादन में कटौती हो सकती है. रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी कहते हैं, "इससे देश पर खर्च का काफी बोझ पड़ेगा." अगर बनाए जाने वाले विमानों की संख्या घटा दी जाती है तो कानपुर से बनकर आने वाले हर विमान की लागत बढ़ जाएगी.

भारत में यात्री विमानों के बड़े बाजार में अप्रत्याशित तौर पर पांव रखने के अलावा 'कासा' एडवांस्ड जेट ट्रेनर (एजेटी) विमानों के बाजार में भी छिपा रुस्तम साबित हो सकता है. भारतीय वायुसेना को इनकी बड़ी संख्या में ज़रूरत है— दस साल की अवधि में करीब 100 विमानों की. फिलहाल भारतीय

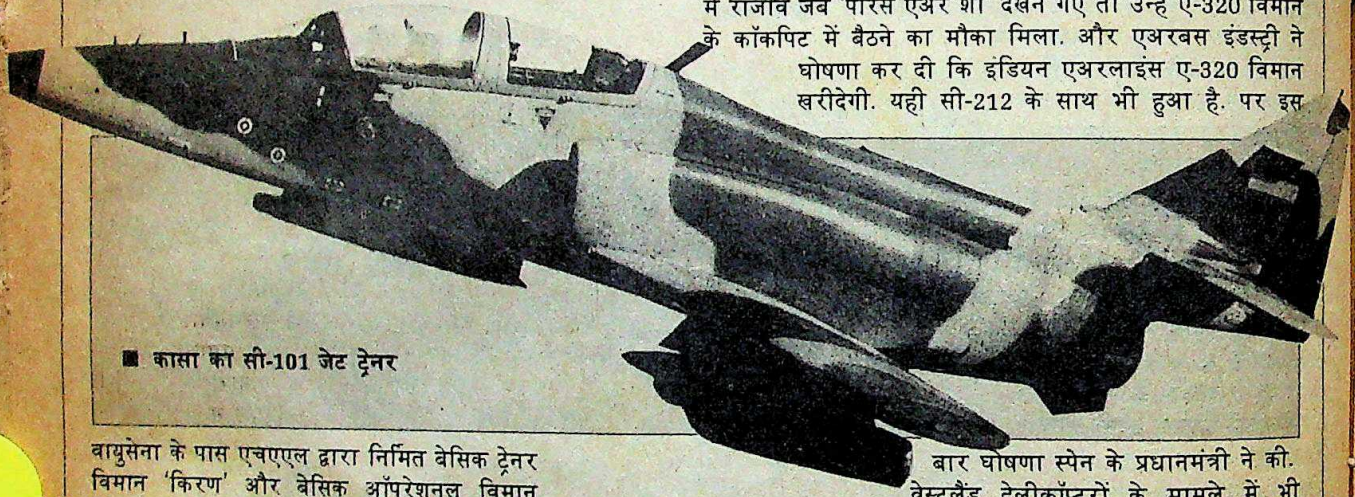

■ कासा का सी-101 जेट ट्रेनर

वायुसेना के पास एचएएल द्वारा निर्मित बेसिक ट्रेनर विमान 'किरण' और बेसिक ऑपरेशनल विमान मिग-21 के बीच कमी को पूरा करने वाला कोई एजेटी विमान नहीं है. अभी तक रक्षा मंत्रालय फ्रांस-जर्मनी के 'अल्फा जेट' और ब्रिटिश विमान 'एअरो-स्पेस हॉक-60' में से किसी का चयन नहीं कर पाया है. 'कासा' वाले एक जाने-माने ट्रेनर सी-101 बनाते हैं जिसका उपयोग युद्ध में हमलावर की तरह भी किया जा सका है. 'कासा' अधिकारी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने राजीव गांधी की मैड्रिड यात्रा के दौरान भारत को सी-101 देने की पेशकश की थी पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें रुचि नहीं दिखाई.

वैसे यह बात समझ में भी आती है. जेट ट्रेनर विमान के लिए स्पेन के अधिकारियों और 'कासा' से बातचीत करने की जिम्मेदारी डॉ.वी.एस. अरुणाचलम की है. मजेदार बात यह है कि रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार अरुणाचलम स्पेन के रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की यात्रा के कई दिन पहले ही मैड्रिड पहुंच गए. दरअसल, भारतीय वायुसेना के लिए 1990 के दशक तक छोटे लड़ाकू विमान बनाने वाले संस्थान 'एअरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी' के अध्यक्ष की हैसियत से अरुणाचलम सी-101 विमान का स्तर आंकने का 'कासा' के

अपने सी-101 जेट ट्रेनर के बूते स्पेन की कासा कंपनी आधुनिक जेट ट्रेनर विमानों की सप्लाई करने की दावेदार बन सकती है. भारत को ऐसे विमानों की जरूरत भी है

अधिकारियों से बातचीत करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं. इसलिए स्पेन की उनकी यात्रा का मकसद दूसरी बातों के अलावा भारतीय वायुसेना के लिए सी-101 की संभावित खरीद पर बातचीत करना भी हो सकता है. राजीव की प्रेस कान्फ्रेंस में सी-212 के बारे में घोषणा और भारत को रुपए में ही विमान बेचने की 'कासा' की पेशकश का मतलब यह हो सकता है कि 'कासा' पर कृपा दृष्टि हो सकती है. वह सी-101 के लिए भुगतान भी रुपयों में ले सकता है.

स्पेन के जेट ट्रेनर विमान का प्रस्ताव सिरे चढ़े या नहीं, पर हाल ही की घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पायलट से प्रधानमंत्री बने राजीव अक्सर विमानन मंत्रालय के लिए अजीब समस्याएं पैदा करते रहते हैं. ए-320 के मामले में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख की अगुआई में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और इंडियन एअरलाइंस के प्रबंध निदेशक को लेकर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी. समिति ने इंडियन एअरलाइंस के उपयोग के लिए बोइंग-757 विमान की सिफारिश की थी. सरकार उस कंपनी को सौदे के लिए पत्र भी लिख चुकी थी. इसके बाद 1985 में राजीव जब 'पेरिस एअर शो' देखने गए तो उन्हें ए-320 विमान के कॉकपिट में बैठने का मौका मिला. और एअरबस इंडस्ट्री ने घोषणा कर दी कि इंडियन एअरलाइंस ए-320 विमान खरीदेगी. यही सी-212 के साथ भी हुआ है. पर इस बार घोषणा स्पेन के प्रधानमंत्री ने की.

वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के मामले में भी राजीव ने संसद में घोषणा की थी कि यह विमान भारत की जरूरतों के मुताबिक नहीं है और अगर वेस्टलैंड कंपनी मुफ्त में भी दे तो इसे नहीं खरीदा जाएगा. विमान और उनके इंजनों के मूल्यांकन के बाद भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने इस हेलीकॉप्टर को रद्द कर दिया था. लेकिन थोड़े ही दिनों बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भारत ने वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्वीकार कर लिया. देश में कुल 27 हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी. इनमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयोग के लिए 'डॉल्फिन' किस्म के 21 छोटे हेलीकॉप्टर और भारतीय वायुसेना के वीआईपी उपयोग के लिए छह बड़े हेलीकॉप्टर शामिल थे. लेकिन सिर्फ ब्रिटेन को खुश करने के लिए एकाएक 21 वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद लिए गए जिससे कुल संख्या 48 जा पहुंची. अतिरिक्त हेलीकॉप्टर अब परेशानी पैदा कर रहे हैं. और उन्हें चलाना भी खतरनाक साबित हो रहा है.

स्पेन के लोग मेहमान के सत्कार में अक्सर कहा करते हैं, "मेरा घर आपका ही घर है." और राजीव सचमुच 'कासा' को अपने घर ही लेकर चले आए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डाल-डाल और पात-पात

अर्जुन सिंह की नई सरकार बनने के छह महीने बाद भी कई मंत्रियों को विधायक निवास के दड़बेनुमा कमरों में ही रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके पूर्ववर्तियों ने अब तक बंगले खाली नहीं किए हैं. इनमें से कई तो अब विधायक भी नहीं रहे. इनमें मोतीलाल वोरा मंत्रिमंडल के ही नहीं बल्कि उसके पहले अर्जुन मंत्रिमंडल (1980-85) के मंत्री भी हैं.

भोपाल के संभागायुक्त ने हाल ही में पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करने के नोटिस दिए तो उन्होंने सीधे-सीधे इनकार कर दिया.

आर.सी. साहू

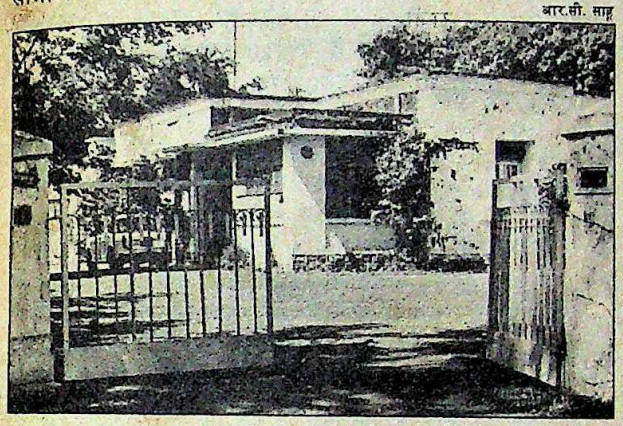

सरकारी बंगला: अनधिकृत कब्जा

वोरा मंत्रिमंडल में मंत्री रहे नेताओं का कहना था कि पहली अर्जुन सिंह सरकार के मंत्रियों ने जब तीन वर्षों से बंगले खाली नहीं किए हैं तो वे ही क्यों खाली करें. यह सुविधा तो उन्हें भी मिलनी चाहिए. बाकी नेताओं का कहना था कि सरकार मंत्रियों के बंगलों पर कब्जा जमाए 26 विधायकों से हटने को कहे तभी वे बंगले छोड़ेंगे. दरअसल, भोपाल में करीब 150 मकान ऐसे हैं जिन पर पूर्व सांसदों, विधायकों और 'सामाजिक कार्यकर्ताओं' ने 'बेजा कब्जा' जमा रखा है. प्रदेश की किसी भी सरकार ने अब तक तो ये मकान खाली करवाने की राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है. ऐसे में लगता है कि राज्य के नए मंत्रियों को फिलहाल छोटे कमरों में ही बैठकर अपना कामकाज चलाना पड़ेगा.

छड़ी दिखाती सरकार

तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की हड़ताल अब वापस ली जा चुकी है. लेकिन समझौता कुछ विचित्र विडंबनाओं के साथ संपन्न हो सका. राज्य सरकार और हड़तालियों के प्रतिनिधियों के बीच जब समझौता वार्ता महत्वपूर्ण दौर में पहुंची तभी राज्य की पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) से आग्रह किया कि वह सभी जिलों में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने का व्यापक अभियान चलाए. पुलिस अधिकारियों ने आरपीएफ से कहा कि वह ऐसे यात्रियों को पकड़ने में उसकी मदद करेंगे.

पुलिस इस बार अपनी तरफ से सहयोग का प्रस्ताव इसलिए रख रही थी क्योंकि राज्य भर के शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों ने वार्ता विफल होने पर राज्य सचिवालय और यहां तक कि मद्रास शहर को घेर लेने की धमकी दी थी. इस स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकार आंदोलनकारियों को रेलगाड़ियों से मद्रास आने से रोकने पर तुली हुई थी, खासकर उस हालत में जब वे बिना टिकट आ रहे हैं. राजधानी में ट्रकों से लोगों का आना रोकने के भी निर्देश जारी किए गए. जुलूस और राजनैतिक सभाओं के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "मोटरगाड़ी कानून के तहत ट्रकों से लोगों को लाने की मनाही है." लेकिन कानून के प्रति उनमें ऐसा प्रेम जागने की वजह थी हड़ताली शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को मद्रास में जमा होने से रोकना. जैसा कि उसी अधिकारी ने स्वीकार किया, "हम अपने मकसद के माफिक कानून पर अमल करना चाहते हैं."

अप्पू के लिए बेकरार

नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के दौरान हजारों का दिल जीतने वाले अप्पू को भुला दिया गया है. तब अरुणाचल प्रदेश के सीजूसा अभयारण्य से लाया गया यह हाथी जंगल में खुला विचरण करने के बजाय सर्कस में खेल दिखाने को मजबूर है.

अप्पू को एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सौंपा था. अब उसने इसे तुरंत भिजवाने की मांग की है. राज्य के मुख्य वन्यजीवन वार्डन जी. एस. थपलियाल कहते हैं कि अप्पू का ऐसा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता. यह सिर्फ अनैतिक ही नहीं बल्कि वन्यजीवन कानून के तहत गैरकानूनी भी है. अपोलो सर्कस के भागीदारों में से एक, सी. श्रीधरन 1982 के एशियाई खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष बूटा सिंह की एक चिट्ठी लेकर पहुंचे थे. उसमें लिखा था कि अप्पू सर्कसवालों को सौंप दिया जाए. इस तरह अप्पू अपोलोवालों के पास पहुंच गया.

पर अरुणाचल सरकार हर हाल में अपना हाथी वापस चाहती है. उसके लिए अदालत में भी जाने की उसकी तैयारी है. इसलिए हो सकता है कि अप्पू के अच्छे दिन फिर लौट आएं.

तकरार फिर इकरार

राज्यसभा सदस्य जगन्नाथ मिश्र ने पिछले पखवाड़े बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद को एक सुखद समाचार से चौंका दिया. विधानसभा सत्र के बाद मिश्र ने बयान जारी किया कि पांच माह पुरानी आजाद सरकार का वे तहेदिल से समर्थन करते हैं. उन्होंने यह भी दुहराया है कि बिहार की समस्याओं को एकबारगी सुलझाना किसी के बस की बात नहीं.

आज़ाद (बाएं) और मिश्र: दोस्ती पर संदेह

लेकिन आजाद और उनके समर्थक, मिश्र के दोस्ताना बयान से संतुष्ट नहीं हो पाए. सत्ताधारी गुट इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मिश्र गुट ने उनकी विधानसभा में तो खिंचाई की ही, खुद मिश्र ने भी बाढ़ नियंत्रण में नाकामी और अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं पर अमल न करने जैसे कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना की है. आजाद विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा में रही उन अफवाहों से भी सशंकित हैं कि राज्य के नेतृत्व में परिवर्तन किया जा सकता है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विवादास्पद नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मसलों पर आंध्र प्रदेश सरकार को सलाह देने के लिए राज्य के हाईकोर्ट के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा संविधान विशेषज्ञ पी.ए. चौधरी को नियुक्त किए जाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. उनकी नियुक्ति की घोषणा उनके अवकाश ग्रहण करने के हफ्ते भर बाद 7 जुलाई को ही कर दी गई थी. राज्य के महाधिवक्ता एफ. मनोहर ने इस पर विरोधस्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनका कहना था, "ऐसी नियुक्ति अनुचित है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 165 में यह काम स्पष्ट

बाल रेड्डी

चौधरी: राजनैतिक नियुक्ति

रूप से महाधिवक्ता के जिम्मे सौंपा गया है. इससे मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और महाधिवक्ता के पदों पर आंच आई है." विवाद से अविचलित चौधरी ने कहा, "अपने नियुक्ति के बचाव की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है." इस नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है.

बहरहाल, राज्य सरकार चौधरी को 10,000 रु. मासिक के अलावा प्रत्येक जिरह के लिए 5,000 रु., 2500 रु. मकान भत्ता, ड्राइवर समेत एक कार तथा महीने में 200 लीटर पेट्रोल और दूसरे भत्ते देगी. शायद चौधरी की विशेषज्ञता की पहली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में रामराव की याचिकाओं पर विचार के दरम्यान होगी. रामराव ने सवाल उठाया है कि क्या हाईकोर्ट को मुख्यमंत्री के खिलाफ भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों वाले जनहित के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार है? इस बीच हाईकोर्ट भी इस पर विचार करेगा कि क्या चौधरी को मुख्यमंत्री की पैरवी करने का अधिकार है?

जिहादियों के जलवे

बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर 'स्टुडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया' (एसआईएमआई) की महाराष्ट्र शाखा इस समस्या को और पेचीदा बनाने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी. इस संगठन ने पिछले पखवाड़े बंबई के मुस्लिम-बहुल इलाकों की दीवारों पर एक पोस्टर चिपकाया. इस पोस्टर में सच्चे मुसलमानों को चेतावनी दी गई थी कि परिवार नियोजन इस्लाम के खिलाफ है. यह मसला अपने आप में काफी नाजुक है.

हालात बदतर होने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री शरद पवार ने चेतावनी दे डाली कि सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रमों की मुखालफत वाली कोई भी ऐसी जोर-जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लेकिन एसआईएमआई की बंबई शाखा के अध्यक्ष मुहम्मद जावेद ने कहा कि हर गैरइस्लामी बात की मुखालफत की जाएगी, भले ही यह राष्ट्रीय नीतियों के खिलाफ ही क्यों न हो.

लेकिन अंतरराष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलनों का निष्कर्ष रहा है कि परिवार नियोजन के कुछ तरीके गैर-इस्लामी नहीं हैं. कुछ तरक्कीपसंद विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि सातवीं शताब्दी में पश्चिम एशिया में आज जैसी जन्म नियंत्रण की वैज्ञानिक जानकारी का अभाव था. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे उपाय वर्जित हैं. पर जावेद अपनी बात पर अड़े हुए हैं. वैसे एसआईएमआई की तनाव पनपाने की क्षमता कल्पनातीत है. उसके अभियान से तो यही लगता है. बहरहाल, कुछ मुसलमान नेताओं ने एसआईएमआई के इस कदम की दबी हुई आवाज में आलोचना करके पवार की मदद कर दी है. पवार कह चुके हैं कि विघटनकारी प्रवृत्तियों से जूझने को प्राथमिकता देंगे.

खेत खाने वाली बाड़

देवदार के वृक्षों से घिरी मेघालय की खूबसूरत राजधानी शिलंग में 40 के दशक में ब्रिटिश वन विशेषज्ञों ने एक बेमिसाल उद्यान लगाया था. लेकिन राज्य के मुख्य वन संरक्षक ए. वाहलांग ने अपना नया दफ्तर बनाने के लिए उद्यान साफ करवा दिया है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले पखवाड़े राज्य सरकार को लिखा कि किसी और मकसद के लिए जंगल नहीं काटा जा सकता लेकिन वाहलांग ने जवाब दिया कि 40 लुप्तप्राय वृक्ष वन विभाग का नया दफ्तर बनाने के लिए काटे गए हैं, इस तरह जमीन का इस्तेमाल वन कार्यों के लिए ही हुआ. केंद्रीय वन अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग के दफ्तर के मौजूदा परिसर में ही नए निर्माण के लिए जगह है. लेकिन वाहलांग इससे सहमत नहीं. उनका कहना है, "मुझे नया दफ्तर चाहिए. यह बहुत जरूरी है." लेकिन केंद्रीय मुख्य वन संरक्षक पी. पटनायक का कहना था, "राज्य में सिर्फ 4 प्रतिशत जमीन पर ही वन बचे हैं और सरकारी दफ्तर बनाने के लिए जंगल काटना किसी कलंक से कम नहीं." राज्य सरकार पर मेघालय वृक्ष संरक्षण कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है. इसके तहत शिलंग में पेड़ काटने पर पाबंदी है.

रमेश मेनन

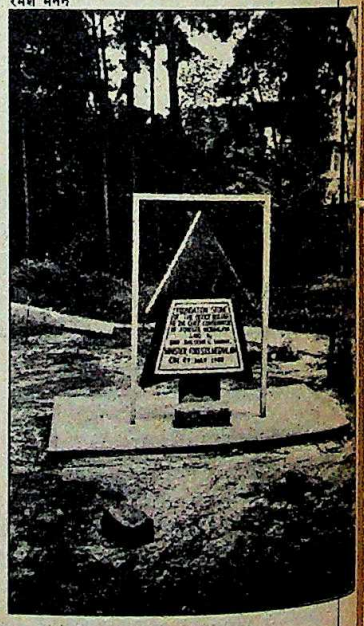

दफ्तर की नींव का पत्थर: पेड़ों की शामत

वृक्षों की जिन लुप्तप्राय किस्मों को काटा गया है उनमें देवदार की कुछ यूरोपीय किस्में—मेटासेक्योआ, पाइनस पेटुला और पाइनस कैरिबिया है. विंडबना यह है कि वन संरक्षक के दफ्तर की नई इमारत की आधारशिला वनमंत्री सालसेंग मरक ने रखी. उन्होंने अपने बचाव में कहा, "मुझे तो यह भान ही नहीं था कि यह उद्यान इतना बहुमूल्य है और इसके इतने महत्वपूर्ण वृक्ष काट गिराए गए हैं." मरक अब कहते हैं कि वे इस नुकसान की भरपाई करने की चेष्टा करेंगे. अभी तक सरकार ने ऐसा उद्यान बनाने के लिए जमीन का कोई टुकड़ा तय नहीं किया है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मारुति की सहयोगी

कार बनाने वाला सरकारी क्षेत्र का मारुति उद्योग एक सहयोगी कंपनी शुरू करने जा रहा है. यह नई कंपनी निर्यात के मकसद से जिग्स, औजार और दूसरे पुर्जे बनाएगी. इसके लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस योजना में सिर्फ चार करोड़ रु. ही लगेंगे जबकि कंपनी को 20 करोड़ रु. तक स्वतंत्र रूप से निवेश की अनुमति मिली हुई है. यह कंपनी अपना माल मारुति की सहयोगी जापानी कंपनी सुजुकी तथा संभवतः दूसरी जापानी कार कंपनियों को भी सप्लाई करेगी. इसी बात को ध्यान में रखकर इसका कारखाना किसी बंदरगाह के पास लगाया जा सकता है. यह योजना मारुति उद्योग को विदेशी मुद्रा कमाने में मदद के लिए तैयार की गई है. (सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि वह कंपनी की 1000 सीसी वाली कार के पुर्जों के लिए साल भर में 26 करोड़ रु. से अधिक की विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराएगी). साथ ही चूंकि निर्यात उन्मुख इकाइयों को अपना 25 फीसदी माल देसी बाजार में बेचने की अनुमति है, इसलिए यह कंपनी मारुति को भी माल देकर दूसरी कंपनियों पर उसकी निर्भरता कम करेगी.

रिलायंस को हरी झंडी

सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र स्थित उसकी लीनियर एल्काइल बेंजीन परियोजना के लिए पूंजी जुटाने के तरीके में बदलाव करने की इजाजत दे दी है. कंपनी ने पहले पूंजी जुटाने के लिए ऋणपत्र जारी करने, विदेशी मुद्रा का कर्ज लेने, माल लेने वाले से कर्ज लेने तथा आंतरिक स्रोतों से 33 करोड़ रु. जुटाने की योजना बनाई थी. सरकार की शर्त है कि 117 करोड़ रु. के ऋणपत्र पूरी तरह परिवर्तनीय होने चाहिए. अब रिलायंस इस परियोजना पर लगनेवाली राशि कहीं और लगा सकती है.

फैसले अलग-अलग

इस सरकारी फैसले से कि सरकारी प्रतिष्ठानों को अपने कामकाज के क्षेत्र से बाहर पांव नहीं पसारने चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम और खुद सरकार की भी मुश्किल हो जाएगी. हाल में ही सरकार ने आईपीसीएल को फ्रांस की मेरियक्स के गठबंधन से गुड़गांव में टीके बनाने का कारखाना लगाने का निर्देश दिया है. फ्रांसीसी कंपनी कनोडिया समूह के साथ गठबंधन करने वाली थी. जब उन्हें लगा कि वित्तीय संस्थाओं से पैसा पाना मुश्किल होगा तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया. और फिर सरकारी आग्रह पर आईपीसीएल आगे आया. अब इस फैसले के बाद सरकार क्या करेगी?.

नाम से नुकसान

अरावली नाम नुकसानदेह है. राजस्थान में कृष्ण कुमार बिड़ला प्रवर्तित अरावली फर्टिलाइजर्स के प्रबंधकों ने पहले तो अंधविश्वास मानकर इस पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन सबसे पहले इस कंपनी की जगह को लेकर प्रदूषण संबंधी विवाद उठा (यह जगह भरतपुर पक्षी अभयारण्य के पास थी). इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के गैस प्राधिकरण ने तय किया कि जब तक कंपनी के कारखाने की जगह का चुनाव नहीं हो जाता, वह इसे दी जाने वाली गैस के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम नहीं करेगा. अब कंपनी को कोटा जिले में जगह दी गई है. लेकिन परियोजना एक साल पिछड़ चुकी है और 10 करोड़ रु. का नुकसान हो चुका है. कंपनी के कर्ताधर्ता अब इसका नाम बदलने की सोच रहे हैं. नया नाम अब तक तय नहीं हुआ है.

खामोश मजदूर

आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक शांति की दृष्टि से 1987 बढ़िया वर्ष था. पिछले साल अनुमानित 2.41 करोड़ श्रम दिवसों का नुकसान हुआ जो पांच वर्षों में सबसे कम है (देखें चार्ट). इससे कम श्रम दिवसों (2.19 करोड़) का नुकसान

चार्ट दी के. शर्मा

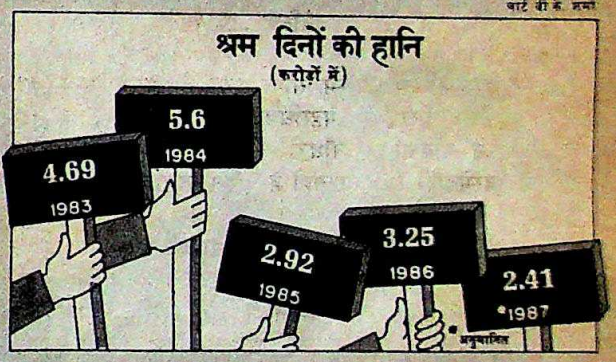

1980 में हुआ था. यह तथ्य चौंकाने वाला है कि पिछले साल हड़तालों से जितने श्रम दिवसों का नुकसान हुआ उससे अधिक नुकसान तालाबंदियों के कारण हुआ. 1986 में उलटी स्थिति थी. देखना है इस साल भी मजदूर शांत रहेंगे या नहीं.

बदलवाएंगे कानून

होटल समूह ताज और ट्रैवेल एजेंसी कॉक्स ऐंड किंग्स मिलकर जल्दी ही एक जनसंपर्क एजेंसी 'गुड रिलेशंस (इंडिया) प्रा. लि.' शुरू करने जा रहे हैं. यह एजेंसी कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के लिए जनसंपर्क करने के साथ ही अपने 'ग्राहकों' की सुविधा के लिए कानून में बदलाव के लिए लॉबीइंग भी किया करेगी. गुड रिलेशंस ऑफ ब्रिटेन से जुड़ी इस एजेंसी में कोई विदेशी पूंजी नहीं लगी है, न ही इसे ब्रिटिश एजेंसी को कोई रॉयल्टी देनी है. बल्कि इन दोनों एजेंसियों ने एक-दूसरे के ग्राहकों की 'मदद' करने का करार किया है. भारतीय एजेंसी अभी दिल्ली और बंबई में अपने दफ्तर खोलेगी और बाद में बंगलूर और कलकत्ता में भी. यह काम के हिसाब से 20 लाख रु. सालाना तक फीस लेगी. ग्रिंडलेज बैंक इसका ग्राहक बन भी चुका है और उम्मीद है कि टाटा समूह की कुछ कंपनियां भी उसका अनुसरण करेंगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थव्यवस्था

कड़वे फैसले लेने की घड़ी

नए वित्तमंत्री को कई दीर्घकालीन समस्याओं से एक साथ जूझना पड़ रहा है

नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में वित्तमंत्री के लंबे-चौड़े दफ्तर में विराजमान शंकरराव भाऊराव चव्हाण इन दिनों अंदेशों से ग्रस्त हैं. उनके कंधों पर कई समस्याओं का बोझ है और उन्हें कुछ कड़वे फैसले लेने पड़ सकते हैं. हालात अगर बहुत जल्द नहीं सुधरे तो उन्हें संसद में नए करों का प्रस्ताव भी पेश करना पड़ सकता है; हालांकि अभी फरवरी में ही नारायणदत्त तिवारी ने अप्रत्याशित रूप से 'उदार' बजट पेश किया था.

इतना ही नहीं, पिछले चार महीनों से विदेशी मुद्रा के आरक्षित भंडार में 1,905 करोड़ रु. की कमी आई है. विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने के लिए चुपचाप हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं. कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का तो मानना है कि इतना ही काफी नहीं. वित्त मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी कहते हैं, "भुगतान संतुलन की गंभीर स्थिति पर अभी ध्यान नहीं दिया गया है."

तीसरी चिंता कीमतों को लेकर है. इस वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में थोक कीमतें मात्र दो फीसदी की दर से बढ़ीं, जो कि इस दशक की सबसे कम बढ़ोतरी थी. फिर भी राजस्व में कमी, खर्चों के बेकाबू हो जाने का खतरा और नतीजतन बजट के घाटे में होती वृद्धि से कीमतें प्रमुख समस्या बन सकती हैं.

आम चुनाव में सिर्फ 17 महीने ही रहे गए हैं इसलिए ऐसे समय नरम रुख अख्तियार किए जाने का तकाजा है. पर चव्हाण ने अपने मातहतों से साफ-साफ कह दिया है कि वे समस्याओं से जूझने में विश्वास रखते हैं. इसलिए हो सकता है आने वाले हफ्तों में करदाताओं को कुछ बुरी खबरें सुनने को मिलें.

प्रशांत पंजियार

घरेलू संसाधन जहां चव्हाण के लिए आफत खड़ी कर रहे हैं, वहीं विदेशी मुद्रा की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है

पर हालात सुधरते लगते हैं. अच्छे मानसून ने विकास दर में अचानक ही तेजी आने की उम्मीदें भी बंधा दी हैं (खुद चव्हाण ने पिछले महीने आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में कहा था कि इस साल आर्थिक विकास कुल मिलाकर आठ फीसदी तक पहुंच जाने की उम्मीद है). लेकिन संसाधनों की मूलभूत समस्या तो कई साल से बनी ही हुई है.

उधर आठवीं पंचवर्षीय योजना (जो अप्रैल 1990 में शुरू होगी) के लिए पैसा जुटाने की तैयारियां भी हो रही हैं. साथ ही इस महीने के आखिर तक योजना आयोग की ओर से यह सलाह आनी भी तय है कि केंद्र राज्यों को संसाधनों की एक और खेप मुहैया करवाए. केंद्र का खाली खजाना इस संभावना से ही कराहने लगा है पर उसे कुछ तो देना ही होगा. यह सिलसिला शुरू हो भी गया है. 1988-89 की पहली तिमाही में आयकर और कंपनी कर की वसूली उम्मीद से काफी कम हुई है. पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में केंद्रीय खजाने में जमा 581 करोड़ रु. के मुकाबले इस बार प्रत्यक्ष कर का राजस्व 400 करोड़ रु. तक ही पहुंच पाया है. नए कर कानूनों की वजह से हो सकता है कि यह अस्थायी चरण हो पर हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं, क्योंकि उत्पाद शुल्क के राजस्व में भी कमी आना शुरू हो गई है.

इसके साथ ही सरकारी खर्च भी काबू से बाहर होता जा रहा है. कई मंत्रालयों के लिए बजट में जितनी रकम का प्रावधान था, वे उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं. लिहाजा, घाटे के रुख को अगर रोका नहीं गया तो वह तेजी से बढ़ता जाएगा. इस साल के बजट में ही 7,484 करोड़ रु. का भारी-भरकम घाटा दर्शाया गया था और इसने अपने रंग दिखाने शुरू भी कर दिए हैं.

वित्त मंत्रालय को एहसास होने लगा है कि ज्यादातर मसले खुद सरकार की नीतियों से ही पैदा हुए हैं. 1988-89 के बजट के बाद दो बड़ी रियायतों (निवेश भत्ते को फिर से लागू करने और निर्यात के मुनाफे को कर मुक्त बनाने) की घोषणा की गई थी. इससे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उम्मीद की किरण

अच्छे मानसून ने सातवीं योजना अवधि में विकास की दर में अचानक ही तेजी आने की उम्मीदें भी बंधा दी है

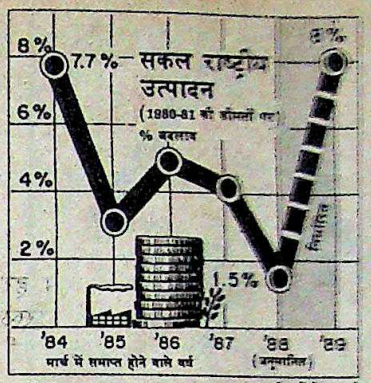

चार्ट बी के वर्मा

सरकारी खजाने को 1,200 करोड़ रु. की चपत लग गई, जो उसकी नासाज हालत के लिए अच्छा नहीं था. करों में दूसरी रियायतों (राष्ट्रीय बचत योजना में रियायतों और आयकरदाताओं के लिए मान्य कटौतियों) से भी समस्या कुछ बढ़ी ही है. उत्पाद शुल्क से मिलने वाला राजस्व भी औद्योगिक विकास की तेजी के अनुरूप नहीं रहा क्योंकि वित्त मंत्रालय को अचानक ही इलहाम हुआ है कि ज्यादातर औद्योगिक विकास तो लघु-उद्योग क्षेत्र में हो रहा है, जो आम तौर से उत्पाद शुल्क से मुक्त है.

अब जिन प्रस्तावों की चर्चा है उनमें बढ़ते सुरक्षा खर्च को पूरा करने के लिए रक्षा कर के अलावा प्रत्यक्ष कर कानूनों में एक नया संशोधन (जिससे संसद में पिछले सत्र के दौरान किए गए बदलाव से हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी) और ऐसे ही दूसरे उपाय शामिल हैं जिनसे हालात की गंभीरता जाहिर होती है. एक विकल्प यह है कि उर्वरकों के दाम बढ़ा दिए जाएं. इसके पीछे तर्क यह है कि मानसून अच्छा होने से उर्वरकों की मांग में कोई अंतर नहीं आएगा. और फिर, विश्व मंडी में इसकी कीमतें बढ़ी ही हैं.

घरेलू संसाधन जहां चव्हाण के लिए आफत खड़ी कर रहे हैं, वहीं विदेशी मुद्रा की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 26 फीसदी की कमी आ गई. अधिकारी कहते हैं कि 'विशेष' परिस्थितियों के चलते ऐसा हुआ और हालात तो सुधरेंगे ही. लेकिन इस समय इस भंडार में जब ढाई महीने के आयात का भुगतान करने योग्य पैसा ही बचा है, हालात इतने संगीन बन गए हैं जितने इस दशक में कभी नहीं रहे. दरअसल जुलाई 1987 और जून 1988 के बीच विदेशी मुद्रा भंडार तीन ही बार 7,000 करोड़ रु. से ऊपर गया है. और वह भी ऐसे समय जब 1981-84 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए 2.9 अरब डॉलर (3880 करोड़ रु.) के कर्ज का भुगतान इस साल सबसे अधिक मात्रा में होगा. इसमें राहत 1992 के बाद ही मिलेगी. इसके अलावा 1960 और '70 के दशकों में लिए गए कर्ज का भुगतान भी बकाया है. विदेशी व्यापारिक कर्जों पर ब्याज का भुगतान भी बढ़ता जा रहा है जिससे विदेशी मुद्रा का निर्गमन बढ़ेगा.

खतरे की यह घंटी पहली बार पिछले साल बजी थी. तब सरकार ने काफी बहस-मुबाहिसे के बाद तय किया था कि '80 के दशक में शुरू हुई उदारवाद की प्रक्रिया को पलटना गलत होगा. इसके बजाय सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाने का फैसला किया जिन पर चुपचाप अमल किया जाता रहा ताकि वे लोगों का ध्यान न आकर्षित कर पाएं.

एक बार तो सरकार ने बैंकरों की स्वीकृति पर आयात में पैसा लगाने के लिए 180 दिन की हुंडी तैयार करने का फैसला कर लिया. इस तरह से मोटे तौर पर 10 लाख डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रु.) जुट गए. साथ ही सरकार ने मिलने वाली विदेशी सहायता को तेजी से बांटना शुरू कर दिया. रक्षा साजो-सामान के आयात का कुछ भुगतान भी वित्त वर्ष की समाप्ति तक रोक लिया गया जिससे इस साल के शुरू में आयात के आंकड़े बढ़ गए.

इस साल अनुमान है कि द्विपक्षीय सहायता और व्यापारिक कर्ज के जरिये जुटाई जाने वाली अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दो अरब डॉलर से अधिक (2,800 करोड़ रु.) हो जाएगी. उम्मीद है कि इसमें से ज्यादातर मुद्रा मिलने वाली विदेशी सहायता के वितरण में तेजी लाकर जुटाई जाएगी (यह विदेशी सहायता करीब 13 अरब डॉलर है). इस बीच हुंडियों में करीब 300 करोड़ रु. की कमी की जा रही है. लेकिन यह कटौती आयात की उन परियोजनाओं में शुरू हो चुकी है जो गैर-जरूरी हैं. प्लास्टिक, ऑटो-मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे आयातोन्मुखी उद्योगों में भी यह कटौती निश्चित है.

लेकिन ये कदम इस तरह फूंक-फूंककर उठाए जा रहे हैं ताकि इससे कोई दहशत न पैदा हो और न ही 'गलत संकेत' मिलें. जाहिर है सरकार अपनी उदारवादी नीति जारी रखने की इच्छुक दिखती है. यह भी उम्मीद है कि निर्यात की नई गति बनी रहेगी और इससे मौजूदा संकट पर काबू पाने में मदद मिलेगी. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी नया कर्ज लेने की कोई संभावना नहीं है.

अचानक उभरा एक विचार घरेलू परियोजनाओं में विदेश हिस्सेदारी का है. सरकार का मानना है कि इससे, थोड़े अरसे के लिए ही सही, विदेशी मुद्रा मिलने में आसानी होगी. निजी क्षेत्र के कई उद्यमों से कहा गया है कि वे अपने विदेशी सहयोगियों को शेयरों में पैसा लगाने के लिए मनाएं. इनमें जापान के सहयोग से बनी बिड़ला की टीवी ग्लास शेल परियोजना भी है. एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक, "भारतीय उद्योग को यह बात

मुसीबत के संकेत

महंगाई काबू में तो दिख रही है. लेकिन सरकारी खर्चों को अंकुश में न रखा गया तो कीमतें मुसीबत बन सकती हैं

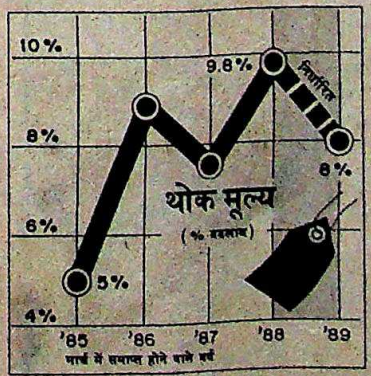

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छीजते भंडार

पिछले चार महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जिस तेजी से कमी आई है उसके कारण विदेशी कर्ज में फंसने का खतरा बढ़ गया है

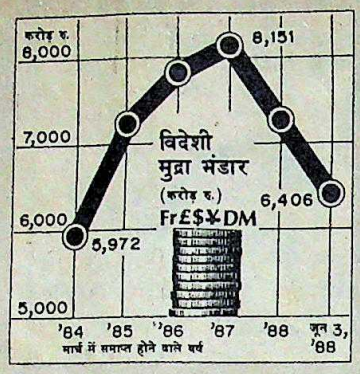

शायद पसंद न हो पर हमें अपनी जरूरतें पता हैं." तकनीकी गठबंधन वाले कुछ उद्योगों पर निर्यातोन्मुखी होने की शर्त भी लगाई जा सकती है. सरकार देर-सबेर प्रमुख परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक उधार की शर्त पर भी अड़ सकती है.

इस बीच वित्त मंत्रालय में वस्तुतः दूसरे सभी मंत्रालयों की अर्जियों का ढेर लग गया है जिनमें अधिक नकदी और अधिक विदेशी मुद्रा की मांग की गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी शिकायत करते हैं, "हम किन गंभीर हालात में फंसे हैं, इसका उन्हें जरा भर एहसास नहीं लगता." रक्षा मंत्रालय (जिसके बजट में पिछले साल कटौती हुई थी और इस साल महज आठ फीसदी बढ़ोतरी की गई) ज्यादा पैसे की दुहाई मचाए हुए है. पर वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसका विरोध करते आ रहे हैं. उनका तर्क है कि रकम गैर-जरूरी मदों के लिए मांगी जा रही है. फिलहाल इसका और ब्यौरा मांगा गया है पर आखिर कुछ रकम दी भी जा सकती है. दूसरे मंत्रालयों के साथ भी यही दांव खेले जा रहे हैं. पर चव्हाण ने अधिकारियों से साफ-साफ कह दिया है कि वे सारे गैर-जरूरी खर्चों के मामलों में कड़ाई से पेश आएं.

समस्याओं से घिरे इस पूरे परिदृश्य की एक अजीब बात यह है कि अर्थव्यवस्था की हालत काफी बेहतर है. इस साल कृषि क्षेत्र में 10 फीसदी और औद्योगिक क्षेत्र में कम-से-कम आठ फीसदी वृद्धि होने की उम्मीद है. आम तौर पर इसे संसाधनों की सुविधाजनक स्थिति माना जाना चाहिए. पर अधिकारियों का मानना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी एक वजह बढ़ता वित्तीय संकट है जिसकी साल-दर-साल अनदेखी की जाती रही (मसलन राजस्व का बढ़ता घाटा). करों का ताना-बाना भी फैलाने की जरूरत है ताकि बढ़ती आमदनियों को इसके दायरे में लाया जा सके.

कुछ लोगों का यह विचार भी है कि पिछले कुछ वर्षों की नीतियों की वजह से ही विदेशी मुद्रा संकट और संसाधनों का अभाव पैदा हुआ है. उदारीकरण की प्रक्रिया बिना निर्यात की संभावनाएं पैदा किए आयातोन्मुखी रही है. उधर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिले कर्ज का ज्यादा हिस्सा उपभोक्ता सामान के समाहार के लिए उपकरण आयात करने और उन्हें बेचने पर लग चुका है. एक वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि "उदारीकरण से अर्थव्यवस्था की ढांचागत समस्याएं नहीं सुलझी हैं."

खाद्य तेलों और पेट्रोलियम जैसी चीजों के आयात पर सीमा न लगा पाने के कारण हालात और ज्यादा बिगड़े हैं. दरअसल पिछले दो साल में पेट्रोलियम का घरेलू उत्पादन लक्ष्य से कम होने और उसकी खपत उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाने के कारण पेट्रोलियम का आयात अकेले पिछले साल ही करीब 50 फीसदी बढ़ गया.

संसाधनों का संकट अब सरकार के ऐन सामने हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सात फीसदी विकास दर हासिल करने की इच्छा जाहिर की है (सातवीं योजना में यह दर 5 फीसदी थी). ऐसा मुमकिन है या नहीं, यह बात इस पखवाड़े के अंत तक, जब पूरे योजना आयोग की बैठक होगी, पक्के तौर पर पता चल जाएगी. पर पिछले कई साल से राष्ट्रीय बचत में ठहराव आने और सात फीसदी विकास दर का लक्ष्य पूरा करने के लिए बचत की दर 22 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी पर पहुंचाने की जरूरत होने के मद्देनजर इसकी संभावना कम ही लगती है.

इस बीच चव्हाण वित्त मंत्रालय के कामकाज के दूसरे पहलुओं पर भी कड़ाई से गौर कर रहे हैं. फिर से छापे पड़ना तो अब लगभग तय है, भले ही यह खबरें मोटी सुर्खियों में न रहें. इसके अलावा वित्तमंत्री निजी तौर पर इस बात की तसदीक करने जा रहे हैं कि गरीबों को मिलने वाले बैंक कर्ज उन तक पहुंच रहे हैं या कहीं और दिए जा रहे हैं. कर्ज मेले भी अगर बैंकिंग के सामान्य कायदों के मुताबिक नहीं चले तो वे गए जमाने की चीज हो जाएंगे.

चव्हाण हालांकि पहले ही संकेत दे चुके हैं कि शेयर बाजार में सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाने के लिए वे कुछ न कुछ करेंगे पर इतना साफ है कि वे सही निवेशकों और फिलहाल शेयर बाजार पर काबिज सट्टेबाजों की जरूरतों में फर्क करते हैं.

कुल मिलाकर मामला साफ है. वित्त मंत्रालय की बागडोर ऐसे विवेकशील व्यक्ति के हाथ में है जो मूलभूत मुद्दों को अपनी स्वभावगत कसौटी पर परखेगा और जो ठीक समझेगा, वहीं करेगा. पर मौजूदा आर्थिक दलदल में मामला उतना सीधा नहीं जितना चव्हाण समझते हैं.

—आनंद पी. रमन

विकास की सुस्त रफ्तार

कर दरों में कटौती से एक दफा तो राजस्व तेजी से बढ़ा लेकिन अब विकास दर में गिरावट साफ नजर आने लगी है

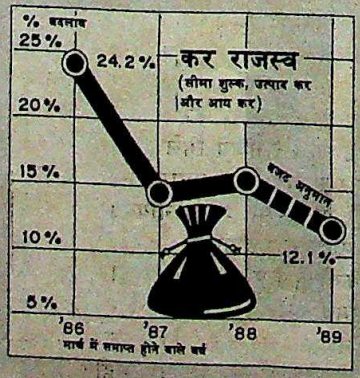

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डनलप

परदे के पीछे जोड़तोड़

नियंत्रण में परिवर्तन की संभावनाओं से कई अटकलें

टायर बनाने वाली डनलप इंडिया लिमिटेड में घटनाओं ने इधर एक विचित्र मोड़ ले लिया है. 430 करोड़ रु. का कारोबार करने वाली इस कंपनी के बोर्ड की 22 जुलाई को कलकत्ता में एक साधारण बैठक हुई जिसमें भारतीय कंपनियों पर धावा बोलने वाले दुबई स्थित उद्योगपति मनोहर (मनु) राजाराम छाबरिया के छोटे भाई किशोर छाबरिया को इसके बोर्ड में शामिल कर लिया गया.

एक पखवाड़े पहले उद्योगपति राम प्रसाद गोयनका और उनके दो बेटे—हर्ष और संजय (डनलप के उप प्रबंध निदेशक) विमान से लंदन गए थे. वहां राम प्रसाद गोयनका जबड़े और कोहनी में रसौली (सिस्ट) की शल्य चिकित्सा करवाने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे. मनु छाबरिया भी वहां पहुंचे और राम प्रसाद गोयनका से भेंट की.

इन दोनों उद्योगपतियों के बीच हालांकि यह शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटीं उससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि गोयनका और छाबरिया के बीच लंदन में ही औपचारिक सौदा हो गया है और गोयनका अपने डनलप के शेयर छाबरिया बंधुओं को बेचने के लिए सहमत हो गए हैं. इससे दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं. जैसा कि गोयनका के एक नजदीकी प्रेक्षक ने टिप्पणी की, "छाबरिया बंधुओं ने महसूस कर लिया है कि साझेदारी नहीं निभती." दोनों पक्षों के करीबी माने जाने वाले एक व्यापारिक बैंकर ने कहा, "इस सौदे का निष्कर्ष स्पष्ट है."

डनलप को हासिल करने में छाबरिया बंधु और राम प्रसाद गोयनका साझीदार थे. दोनों दिसंबर 1984 में कंपनी के लगभग 10 फीसदी विदेशी शेयर खरीदने के लिए एक साथ हो गए. लेकिन दोनों ने ये शेयर कितने में खरीदे, अभी तक किसी को मालूम नहीं. पर दोनों की साझेदारी तनावपूर्ण ही रही है और दोनों पक्ष इस धनी-मानी विशाल कंपनी पर अपना नियंत्रण जमाने के लिए परदे के पीछे लड़ते रहे हैं. एक बार तो छाबरिया बंधुओं ने डनलप के मुख्य वित्तीय अधिकारी को बरखास्त करने की मांग तक की थी लेकिन गोयनका ने इस मांग पर कभी विचार नहीं किया.

डनलप छोड़ने से राम प्रसाद गोयनका की प्रतिष्ठा कम हो सकती है. यह फैसला टालना ही उनके लिए बेहतर है

किशोर छाबरिया के डनलप के बोर्ड में होने से कंपनी पर छाबरिया बंधुओं के वर्चस्व की उम्मीदें बढ़ गई हैं

राम प्रसाद गोयनका के साथ हुए समझौते के बारे में किशोर और मनु दोनों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया. राम प्रसाद और उनके बेटे संजय मिले ही नहीं. लेकिन उनके एक संबंधी ने बताया कि छाबरिया बंधुओं और राम प्रसाद गोयनका के बीच कोई सौदा नहीं हुआ है.

तकनीकी रूप से यह सही हो सकता है. भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सौदा तो होने वाला है लेकिन कितनी जल्दी होगा कहा नहीं जा सकता. महीनों पहले दोनों पक्षों ने फैसला किया था कि डनलप से या तो छाबरिया हट जाएंगे या फिर गोयनका ताकि इनमें से किसी एक के लिए रास्ता साफ हो जाए. समझौते की शर्तों के मुताबिक दोनों के बीच सहमति हुई थी कि वे एक दूसरे के शेयरों पर बोली लगाएंगे और जिसकी बोली सबसे अधिक होगी, डनलप पर उसी का कब्जा होगा.

अपनी अपेक्षाकृत अधिक मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण छाबरिया बंधु गोयनका के शेयर खरीदने के लिए बेहद उत्सुक रहे हैं. हालांकि मनु डनलप के अध्यक्ष हैं लेकिन कंपनी वस्तुतः संजीव गोयनका ही चलाते हैं. एक चर्चा के मुताबिक, राम प्रसाद गोयनका ने छाबरिया बंधुओं की इस मांग को हर बार नजरअंदाज कर दिया था कि मामला सुलझा लिया जाए. लेकिन छाबरिया बंधु कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे.

छाबरिया बंधुओं और गोयनका के बीच चल रही समझौता वार्ता अब शायद निर्णायक दौर में पहुंच गई है. यदि इस वार्ता के नतीजे के बतौर कोई सौदा हो गया तो छाबरिया बंधुओं का अगला कदम डनलप इंडिया की मूल कंपनी, ब्रिटेन की डनलप होल्डिंग्स के 30 फीसदी शेयर भी हासिल करना होगा. बताया जाता है कि डनलप होल्डिंग अपनी भारतीय कंपनी के शेयर बेचने के लिए इच्छुक है.

जहां तक गोयनका का सवाल है, डनलप से अगर वे हट गए तो उनकी इज्जत में थोड़ा बट्टा लग सकता है. लेकिन वे डनलप से हटने का फैसला देर से कर सकते तो उनके लिए बेहतर होता.

जहां तक डनलप का सवाल है, कंपनी के नियंत्रण में किसी तरह का परिवर्तन किया गया तो यह उसके लिए डांवाडोल स्थिति का सबब बन सकता है. यह कंपनी भारी औद्योगिक रसायनों, उत्कृष्ट रसायनों और सिंथेटिक तथा प्राकृतिक रबर उत्पादनों के कई क्षेत्रों में पांव पसारने वाली है. इस तरह यह बहु-उत्पाद वाली कंपनी बन जाएगी. खैर, हवा का जो रुख है उसके मुताबिक डनलप को अभी भी उसी रास्ते से सफर करना है, चाहे वह रास्ता ऊबड़-खाबड़ हो या सपाट हो.

—आनंद पी. रमन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ईपी दवाएं

विकृति पर विजय

नुकसानदेह दवाओं पर प्रतिबंध

भारत भी दूसरे विकासशील देशों की तरह काफी लंबे समय से उन दवाइयों का कूड़ेदान बना हुआ है जो विकसित देशों में प्रतिबंधित हैं. लिहाजा सरकार ने जब पिछले महीने इस आधार पर अधिक मात्रा वाली ओस्ट्रोजेन-प्रोजेस्टेरोन (ईपी) मिश्रित दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया कि ये 'बेहद नुकसानदेह, खतरनाक और चिकित्सीय दृष्टि से अप्रमाणिक' हैं तो लोगों को ताज्जुब हुआ. भारत में इन दवाइयों का कारोबार 7 करोड़ रु. का है.

इन दवाइयों पर प्रतिबंध दवा उद्योग (खासतौर पर यूनीकेम और इनफार) और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच छह साल तक चली लड़ाई के बाद लगाया गया. निर्माताओं का दावा था कि यह दवा संचायक अमीनोरोहिया (मासिक धर्म का न आना) जैसे रोग में फायदेमंद है. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना था कि इससे सस्ती और कम नुकसानदेह दवा नोरेथिस्टेरोन उपलब्ध है जिसे कम मात्रा में लिया जाता है. उनकी यह भी दलील थी कि अमीनोरोहिया का इलाज कृत्रिम हार्मोंस देने पर नहीं बल्कि इस बीमारी के कारणों को खत्म करने पर केंद्रित होना चाहिए. भारत में ये कारण हैं— टीबी और रक्ताल्पता.

कुछ डॉक्टरों की दलील थी कि अधिक मात्रावाली ईपी दवाइयां कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उपयोगी होती हैं. लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक यह कोई निर्णायक सबूत नहीं है. दूसरी बात यह कि गर्भवती महिला को अधिक मात्रावाली ईपी दवाएं देने से भ्रूण को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है. दरअसल 1976 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एचपीटी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी.

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि दुनिया भर के दवा निर्माता अब हार्मोंस का उत्पादन घटा रहे हैं. लेकिन यूनीकेम (1987 में इसकी ईपी दवाओं का कारोबार 5.6 करोड़ रु. का था) और इनफार (इसकी ईपी दवाओं का कारोबार 94.31 लाख रु. का था) ने इसके उलट सबूत पेश किए. अध्ययनों के मुताबिक, अधिक मात्रावाली ईपी मिश्रित दवाएं पूरी तरह से निरापद हैं. यूनीकेम के प्रबंध निदेशक प्रकाश मोदी की दलील थी कि बाजार में तीन दशक से बिकने वाली ये दवाएं यदि नुकसानदेह थीं तो कार्यकर्ताओं ने हजारों विकृत बच्चों को सबूत के रूप में क्यों नहीं पेश किया.

लेकिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईपी की एक बार में अधिक मात्रा होना ही खतरनाक है. लगातार थोड़ी मात्रा लेना नहीं जैसा कि गर्भ निरोधक गोलियों में होता है. कलकत्ता में इनफार के विपणन प्रबंधक सात्यकी राय की दलील है कि दवा विक्रेताओं के गलत कामों के लिए किसी कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. यूनीकेम के कंपनी सचिव एल.एन गोडबोले कहते हैं कि यदि इन दवाइयों पर महज इसलिए प्रतिबंध लगाया जाना है कि दवा दुकानों में इनकी बिक्री से व्यापक दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है तो भारत में आधी दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है.

उपभोक्ता संगठनों ने 1979 में डॉ. पलनियप्पन द्वारा मद्रास में किए गए अध्ययन के बाद से ही आवाज उठानी शुरू कर दी थी. डॉ. पलनियप्पन का दावा था कि मद्रास मेडिकल कॉलेज में पैदा हुए (5,000 शिशुओं में) 51 विकृत बच्चों में से 38 फीसदी की माताओं ने माना कि उन्होंने अधिक मात्रा वाली ईपी मिश्रण की दवाएं ली थीं. यहीं से लड़ाई शुरू हो गई. भारत के दवा नियंत्रक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिश पर 1982 में अधिक मात्रा वाली ईपी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया. लेकिन इनफार और यूनीकेम ने इस तरह के आदेश जारी करने के दवा नियंत्रक के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता और बंबई हाईकोर्टों से स्थगनादेश ले लिए. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट ने अधिक मात्रावाली ईपी मिश्रण की दवाओं की उपयोगिता या उनसे होने वाले भारी नुकसान की तसदीक करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई का आदेश दे दिया. कई मशहूर स्त्रीरोग विशेषज्ञों ने इन दवाओं का समर्थन किया. लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इससे प्रभावित नहीं हुई और उसने 1987 के उत्तरार्ध में फिर इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी. इसी के बाद भारत के दवा नियंत्रक ने पिछले पखवाड़े इन दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया. अब मोदी जहां कहते हैं कि "सरकार की इच्छा सिर माथे," वहीं गोडबोले दावा करते हैं कि यह गर्भ निरोधकों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत है.

दवाइयों पर प्रतिबंध के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते-लड़ते थक चुके 'यूनीकेम' के मोदी कहते हैं, "सरकार की इच्छा सिर माथे पर"

लेकिन शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान करने वाले रवि दुग्गल ने. उनका कहना है कि अधिक मात्रावाली ईपी दवाओं पर सुनवाई करने वाले बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में कोई महिला नहीं थीं.

बहरहाल, ईपी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना दुग्गल और उनके जैसे दूसरे लोगों की जीत ही है. इस फैसले से खुश एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स ऐक्शन फॉर सेफ्टी ऐंड हेल्थ के संयोजक अरुण बल ने कहा, "पूरी दुनिया में नुकसानदेह मानी जाने वाली दवा पर भारत में पहली बार प्रतिबंध लगाया गया है." उपभोक्ता संगठन अब खांसी की तरल दवाओं, टॉनिकों और एंटीबायोटिक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

उफान के लक्षण

भविष्य भी सुनहरा

पिछले महीने के शुरू में शेयरों की कीमतें धूल चाटती दिखाई दे रही थीं. पर लगता है यह मिजाज कुछ समय के लिए ही था. पिछले पखवाड़े शेयर बाजार निराशा के गर्त से उबर आया. कीमतों में आए उछाल से बाजार की भीतरी मजबूती एक बार फिर साबित हो गई.

वित्तीय संस्थानों ने बाजार में जो खरीदारी की उससे रुख ही पलट गया. उनके इस कदम से कीमतें चढ़ गईं. साथ ही वित्तमंत्री शंकरराव चव्हाण द्वारा यह संकेत दिए जाने से कि लिवालों को करों में राहत दी जाएगी, शेयरों के दाम ऊपर चढ़ने लगे.

फिर भी बाजार का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. अच्छे मानसून (जिनसे अनाज की अच्छी पैदावार की गारंटी मिल रही है) और कंपनियों के अच्छे कामकांज ने इसे और भी दुरुस्त कर दिया है. इधर

चार्ट बी.के. शर्मा

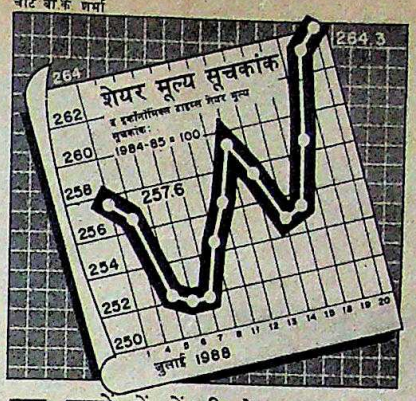

कुछ हफ्तों में सेंचुरी टेक्सटाइल्स और एसकेएफ बीयरिंग जैसी कंपनियों ने अपनी आमदनी में खासी बढ़ोतरी की घोषणा की है. लिहाजा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर की तरह इनके शेयरों की भी खरीदारी बढ गई.

बाजार के इस सुधार को दर्शाने वाली 'द इकॉनामिक टाइम्स' का सूचकांक पिछले पखवाड़े 251.8 से बढ़कर 264.3 पर पहुंच गया. फिर भी यह इस साल की बुलंदी 272.2 से कुछ नीचे ही था. सूचकांक जून के पहले हफ्ते में उस ऊंचाई पर पहुंचा था.

जहां तक तात्कालिक भविष्य का सवाल है, अगले पखवाड़े शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ भी सकती हैं और नहीं भी बढ़ सकती बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि बाजार को मंदा न पड़ने देने के लिए सरकार कैसा रवैया अख्तियार करती है. अभी तो यही लगता है कि दीर्घकालीन अवधि में शेयरों की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ती ही रहेंगी.

यह होना ही है और इस बात के समर्थन में कुछ पुख्ता तथ्य भी हैं. मिसाल के लिए साझा कोष शेयर बाजार में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे. इनमें से कई तो नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी. एक वजह यह भी है कि इस साल 180 कंपनियां जनता से 3,353 करोड़ रु. हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठी हैं. कंपनियों की यह संख्या पिछले साल से कम है. तब 284 कंपनियों ने शेयर जारी किए थे. पर कंपनियों में हौसला इस कदर है कि वे अब बड़े निर्गमन की तैयारी कर रही हैं.

फिलहाल, दलाल राहत के लिए नॉर्थ ब्लॉक की ओर देख रहे हैं. बाजी अभी वित्तमंत्री के हाथ में है. अगर उन्होंने एहसान करने का फैसला किया तो आने वाले दिनों में कीमतें जरूर नई बुलंदी पर पहुंच सकती हैं.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 20.7.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	41.00	30.25	41.00	3.00 +
एसोसिएटेड सीमेंट	265.50	128.50	231.00	19.00 +
एटलस कोप्को	63.50	33.50	52.00	6.00 +
एशियन पेंट्स	175.00	128.75	160.00	10.00 +
बजाज ऑटो	520.00	187.50	246.25	15.00 +
बड़ौदा रेयॅन	282.50	140.00	257.50	22.50 +
बाटा इंडिया	77.25	50.50	66.50	3.00 −
भारत फोर्ज	147.00	101.00	127.00	3.00 +
बिरला जूट	47.00	32.25	40.50	0.25 +
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	35.00	1.00 +
बॉम्बे डाइंग	159.50	94.00	117.00	24.00 −
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	91.00	4.00 +
बुक बांड	98.00	75.00	86.50	2.50 +
सेंचुरी स्पिनिंग	897.00	617.50	890.00	60.00 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	64.50	—
कोलगेट	222.50	160.00	215.00	15.00 +
सायनामिड	52.00	33.00	42.00	—
डीसीएम	47.50	28.00	41.75	0.75 −
डनलप	86.50	69.50	73.75	1.75 +
ईआई होटल्स	54.00	38.00	50.00	1.00 +
एस्कार्ट्स	57.00	37.00	50.00	3.00 +
फिनोलेक्स केबल्स	435.00	272.50	427.50	37.50 +
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	93.50	126.50	9.50 +
गरवारे नाइलोन	43.00	20.00	43.00	5.00 +
जी.ई. शिपिंग	33.75	20.80	30.12	3.37 +
गुजरात स्टेट फर्टि.	140.00	75.00	138.00	18.00 +
ग्रासिम इंडिया	111.00	81.50	110.00	5.00 +
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	88.00	3.00 +
हिंदुस्तान सिवा	520.00	332.50	505.00	55.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	81.25	5.00 +
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	69.00	3.25 +
हिंदुस्तान मोटर्स	27.00	15.80	24.40	2.60 +
आई.ई.एल.	43.75	31.00	38.00	2.00 +
इंडियन आर्गेनिक	27.00	15.00	26.50	7.50 +
इंडियन रेयॅन	75.00	46.00	74.50	6.50 +
इंडाल	223.75	133.75	168.75	8.75 +
इंगरसॉल-रैंड	335.00	205.00	267.50	22.50 +
आई.टी.सी.	46.75	30.00	46.00	6.50 +
जे.के. सिंथेटिक्स	74.00	45.50	64.75	2.50 +
काइनेटिक इंजी.	285.00	161.25	227.50	5.00 +
किर्लोस्कर क्युमिंस	59.00	48.00	55.50	1.00 +
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	267.50	15.00 +
लारसन-टुब्रो	101.50	75.50	99.50	6.50 +
लिप्टन	67.00	52.00	62.00	0.50 +
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	15.50	2.25 +
मदुरा कोट्स	77.00	59.00	69.00	—
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	48.50	59.50	3.00 +
मिल्क फूड	140.00	72.50	132.50	12.50 +
मोटर इंडस्ट्रीज	630.00	447.50	607.50	60.00 +
मुकुंद आयरन	97.00	72.50	87.50	4.50 +
नेशनल आर्गेनिक	525.00	390.00	460.00	10.00 +
निरलॉन	16.00	5.00	9.75	0.25 +
ओरके सिल्क मिल्स	51.00	17.00	30.50	1.50 +
ओटिस एलिवेटर	215.00	161.25	185.00	12.50 +
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	37.00	24.50	30.50	1.00 +
फाईजर	79.50	50.00	63.00	1.00 +
प्रीमियर ऑटो	39.50	23.00	32.50	3.50 +
रैनबेक्सी	120.00	72.00	76.25	3.75 −
रेमंड	96.00	41.50	49.00	—
रॉकिट ऐंड कोलमैन	227.00	175.00	213.00	1.00 +
रिलायंस इंडस्ट्रीज	213.00	69.00	214.50	33.50 +
शॉ वैलेस	132.00	50.50	55.00	0.50 +
श्रीराम फाइबर्स	62.50	32.50	54.75	4.25 +
सीमेंस इंडिया	80.00	56.50	72.00	8.00 +
एसकेएफ बैयरिंग्स	1375.00	1058.00	1370.00	95.00 +
स्पिक	60.25	23.50	53.75	8.50 +
टाटा स्टील	907.50	568.75	808.75	26.25 +
टेल्को	701.00	340.00	655.00	32.50 +
वाम आर्गेनिक	103.00	75.00	90.00	3.00 −
विम्को	24.00	11.00	17.75	1.25 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	11.4103	11.2889
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.0902	1.0786
बहरीन	दीनार	1	37.2323	37.1222
बांग्लादेश	टका	100	45.5220	45.4783
कनाडा	डालर	1	11.8574	11.7358
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0122	1.9916
मिस्र	पौंड	1	9.3630	9.3012
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3068	2.2497
हांगकांग	डालर	1	1.8164	1.7983
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0890	0.0833
ईरान	रियाल	100	19.9732	19.9000
इटली	लीरा	100	1.0326	1.0000
जापान	येन	100	10.8225	10.5485
केन्या	शिलिंग	1	0.7794	0.7126
कुवैत	दीनार	1	51.3532	51.2926
मलेशिया	डालर	1	5.3981	5.3409
मारीशस	रुपया	1	1.0360	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6300	0.5992
हालैंड	गिल्डर	1	6.7886	6.7167
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7880	0.7129
सिंगापुर	डालर	1	6.9342	6.8560
स्पेन	पेसो	1	0.1190	0.1001
श्रीलंका	रुपया	1	0.4432	0.4180
स्वीडन	क्रोना	1	2.2278	2.2048
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.2412	9.1443
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1420	0.1229
थाईलैंड	बहत्त	100	55.7432	55.6536
ब्रिटेन	पौंड	1	24.1225	24.9923
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	14.1945	14.0548
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.8200	3.7921
सोवियत संघ	रूबल	1	16.2662	16.2082
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	7.7760	7.5815

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 21.7.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उथलपुथल यहां, केंद्र कहीं और

सुदूर वाशिंगटन में घटी घटनाएं भी भारत की नौकरशाही में उथलपुथल मचा सकती हैं. विश्व बैंक में भारत के दोनों कार्यकारी निदेशकों, सी.आर. कृष्णास्वामी राव साहब और अर्जुन सेनगुप्त का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है.

लगता है सरकार ने इन दो में से एक पद के लिए व्यक्ति का चुनाव कर लिया है. ये सज्जन हैं, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बिमल जालान. उम्मीद है कि जालान जल्दी ही वाशिंगटन जाने की तैयारी शुरू करेंगे. एक संभावित उम्मीदवार सेनगुप्त भी हो सकते हैं. यह भी कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर रहीं सरला ग्रेवाल का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो सेनगुप्त उनकी जगह पर आ सकते हैं.

सेनगुप्त (बाएं) और जालान: दौड़ में

दूर की कौड़ी लाएंगे

सरकार ने दूरसंचार विभाग को उपकरणों के आयात की मंजूरी अंततः दे दी. सो, अब वह विदेशी बाजार में खरीदारी के लिए निकल सकता है.

विभाग जिन चीजों को खरीदना चाहता है उनमें जापान की एनईसी कंपनी द्वारा निर्मित 32,000 लाइनों वाले छोटे डिजिटल एक्सचेंज और स्वीडन की एरिकसन कंपनी द्वारा तैयार मोबाइल टेलीफोन शामिल हैं. ये टेलीफोन बंबई में शुरू होने वाले सेल्युलर टेलीफोन योजना में इस्तेमाल होने हैं. वैसे 'सी-डॉट' के सलाहकार सैम पित्रोदा इस योजना के खिलाफ इन दिनों जोरदार अभियान चला रहे हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग सिस्टम बनाने वाली दूसरी फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव अभी लटका पड़ा है. लेकिन इस बीच फ्रांस की सीआईटी अलकेटल कंपनी से 99,000 लाइनों वाले डिजिटल एक्सचेंज के आयात की बातचीत चल रही है.

इतना ही नहीं, विभाग ने महानगरों के लिए ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों के लिए जो निविदा जारी की थी, उसमें कई विदेशी कंपनियों ने भारी दिलचस्पी दिखाई है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंप्यूटर और दूरसंचार कंपनी सीएमसी ने पुराने एक्सचेंजों में ही कुछ नए उपकरण लगाकर उनका स्तर सुधारने का प्रस्ताव रखा था.

अधिकारियों ने सीएमसी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए यह कहा था कि नए जोड़े जाने वाले उपकरण तुरंत उपलब्ध नहीं हैं और अगर नए उपकरण मंगाए नहीं गए तो देश की संचार व्यवस्था में जल्दी सुधार नहीं हो सकता. पित्रोदा भले ही इस तर्क से सहमत न हों लेकिन वे यह बाजी हार चुके हैं.

सुलह के सिवा चारा नहीं

भारतीय उद्योग एवं व्यापार संघ (फिक्की) और एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स (एसोचैम) ऊपरी तौर पर खुल कर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे हैं. महीनों पूर्व फिक्की के कुछ सदस्य एसोचैम में चले गए तो दोनों संघों में खुद को देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक संघ बताने की होड़ भी चल पड़ी थी. लेकिन भीतर ही भीतर इनमें गुपचुप मेलमिलाप भी चल रहा है. दोनों संघों के बीच तू-तू मैं-मैं को समाप्त करने के लिए एसोचैम के अध्यक्ष ललित थापर और फिक्की के उपाध्यक्ष रौनक सिंह हाल ही में एक भोज पर मिले. दोनों ने उम्मीद जताई कि विवाद जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे.

थापर (बाएं) और सिंह: सुलह की कोशिश

इन दोनों की इस सदीच्छा पर तो किसी को संदेह नहीं है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना भारी चुनौती है. विभिन्न देशों के साथ बने 34 संयुक्त व्यापार परिषदों में भारत का प्रतिनिधित्व फिक्की ही करता रहा है. अब एसोचैम भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहा है.

खैर, फिक्की के सामने सुलह के अलावा कोई और रास्ता नहीं है. इस विवाद से ऊबी सरकार संयुक्त व्यापार परिषदों का मामला देखने के लिए स्थायी सचिवालय बनाने की सोच रही है. तब फिक्की कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसी का सचिवालय ऐसे मामले देखता रहा है.

नफासत से चले नश्तर

कर विभाग वालों को एहसास हो गया है कि डंडे के जोर पर ही सब कुछ नहीं होता. कभी-कभी नश्तर नफासत से भी चलना जरूरी है. कुछ महीने पहले उन्होंने कर चोरी पकड़ने के लिए छापे मारने की जगह सर्वेक्षण जैसा गुपचुप तरीका अपनाया. अखबारों में विज्ञापन देकर आयकर विभाग सूचना देता है कि फलां व्यापारिक इलाके में विभाग के इंस्पेक्टरों की टोलियां जाएंगी और वे व्यापारियों की कर संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगी.

और विभाग का तीर निशाने पर लग गया. उसके करदाताओं की सूची में ढेर सारे नए और स्थायी नाम जुड़ गए. पिछले साल करीब छह लाख व्यापारिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण हुआ और पांच लाख से अधिक नए करदाता ढूंढ़े गए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नैतिकता का तकाजा

तमाम दूसरे अखबारों से पहले कोई खबर छाप देना यानी अखबारनवीसों की भाषा में जिसे 'स्कूप' कहते हैं वह किसी भी अखबार के लिए अमूल्य चीज होती है. हर संवाददाता हमेशा उसके ही सपने देखता रहता है. और क्यों न देखे? 'स्कूप' उसके लिए तमगे के समान जो होते हैं!

इसलिए जाहिर है स्कूपों की भरमार रहती है. 'द हिंदू' ने पिछले दिनों बोफोर्स घोटाले से संबंधित जो दस्तावेज छापे वे उच्च कोटि के स्कूपों में गिने जा सकते हैं. वैसे तो छोटे-मोटे स्कूप छपते रहते हैं, एकाध दिन चर्चा का विषय बनते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं.

किसी संवाददाता को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में ही कोई स्कूप हाथ लग जाए तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि यह अक्सर किसी प्रयोजन से प्रेरित होता है. इसलिए उसकी पूरी तरह जांच-परख जरूरी है. यदि खबर सही साबित हो तथा जनहित में हो तभी उसे प्रकाशित करना चाहिए. आम तौर पर 'सूत्र' कहीं भी मिल सकते हैं और गोपनीय ही होते हैं और उन्हें गोपनीय रखना भी चाहिए. कभी-कभी किसी अखबार को कोई अप्रत्याशित स्कूप हाथ लग जाता है. ऐसे मामले में तो जांच-परख और भी जरूरी होती है.

'इंडियन एक्सप्रेस' ने कर्नाटक जनता पार्टी विवाद को लेकर 10 जुलाई को जब 'द कान्सपीरेटर ऐज रेफरी' (षड्यंत्रकारी ही पंच बना) शीर्षक स्कूप को प्रमुखता से छापा तो उसकी मंशा समझ में आती है. रिपोर्ट जनता पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह और कर्नाटक में जनता पार्टी के असंतुष्ट नेता एच. डी. देवगौडा के बीच टेलीफोन वार्ता से संबंधित थी. नई दिल्ली से लिखी गई इस रिपोर्ट में टेलीफोन वार्ता के कुछ अंश छापे गए और इसे 'केंद्रीय सरकार के सूत्रों' के हवाले से प्राप्त बताया गया. दरअसल यह रिपोर्ट अजीत सिंह और चंद्रशेखर पर एक्सप्रेस के इस आरोप को सही ठहराती है कि ये दोनों नेता मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को राज्य में ही उलझाए रखने के लिए असंतुष्टों को शह दे रहे हैं.

एक्सप्रेस ने अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए 13 जुलाई को संपादकीय लिखा, "इस टेलीफोन वार्ता की सचाई पर न तो अजीत सिंह ने और न ही देवगौडा ने कोई सवाल उठाया है." लेकिन इस रिपोर्ट से जुड़े राजनीतिकों और इससे प्रभावित लोगों की बात छोड़ दें तो भी यह आश्चर्यजनक ही है कि रिपोर्ट छापने के हफ्ते भर बाद भी एक्सप्रेस ने सरकारी मशीनरी (राज्य हो या केंद्र) द्वारा राजनीतिकों की टेलीफोन वार्ताओं को टेप करने की अनैतिकता पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा. रिपोर्ट की सचाई की जांच करके उसे छापना तो एक बात है पर किसी भी ऐसे नागरिक के टेलीफोन को गैरकानूनी ढंग से टेप करना जिस पर किसी तरह का कोई गंभीर आपराधिक या दूसरा मामला न हो, बिलकुल अलग ही बात है.

कार्टून: अजीत नैनन

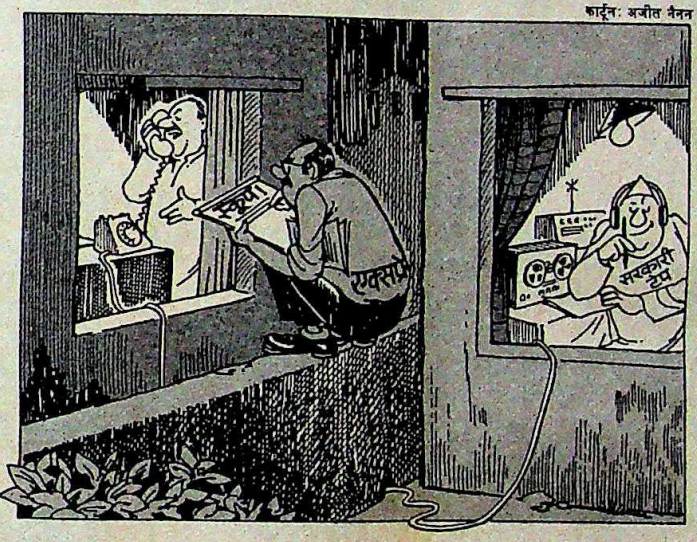

टेलीफोन टेप करना नाजायज है तो वह सबके लिए नाजायज है भले ही उसके लिए ऐसे स्कूप की बलि देनी पड़े जो संपादकीय नीति के समर्थन में हो

अखबारवाले अक्सर यह शिकायत करते रहते हैं कि नागरिक अधिकारों के हनन के प्रति लोगों में नैतिक रोष समय के साथ मद्धिम पड़ता जा रहा है. इसीलिए अखबारवाले नागरिक अधिकार के मुद्दों को समय-समय पर उठाते रहते हैं. डाक विधेयक की, जिससे सरकार को लोगों के पत्रों को खोलने का निरंकुश अधिकार मिल जाता, अखबारों ने एक स्वर से निंदा की थी. यह एक सुखद अनुभव था. गनीमत है, आज भी यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पड़ा हुआ है.

अफसोस की बात तो यह है कि एक्सप्रेस इस छोटे-से स्कूप के बहाने अपने 'सूत्र' की भर्त्सना करके पत्रकारिता के नैतिक मानदंडों के प्रति निष्ठावान बना रह सकता था. अगर उसे इसकी फिक्र होती तो उसने स्कूप छापने का लालच छोड़ दिया होता. आलोचना में पक्षपात बरतने से अखबारों की साख नहीं बढ़ेगी.

राजनीतिकों का मतलब सधता हो तो वे टेलीफोन टेप करने जैसी गैरकानूनी कार्रवाई को भी स्वीकार कर सकते हैं. लेकिन यदि प्रेस को अपने मकसद के प्रति ईमानदार बने रहना है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. यह जिम्मेदारी दिन के उजाले की तरह साफ है. यदि टेलीफोन टेप करना नाजायज है तो वह सबके लिए अनिवार्यतः नाजायज है भले ही उसके लिए ऐसे स्कूप की बलि देनी पड़े जो अखबार की संपादकीय नीति के पक्ष में क्यों न हो.

इमरजेंसी ने कई अखबारों की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी थी. उसके बाद से अखबारों ने प्रतिष्ठा बहाल करने में कड़ी मेहनत की है. अब जबकि अगला आम चुनाव सिर पर है और विपक्षी दलों को लगता है कि वे अगला चुनाव जीत सकते हैं, तो ऐसे में प्रेस को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है. इसे लोगों को यह कहने का फिर मौका नहीं देना चाहिए कि प्रेस ने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने के बजाय राजनीति में मशगूल होकर देश को फिर से धोखा दिया.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नगालैंड

मुश्किलों से घिरी ममता

परित्यक्त बच्चों को सहारा देने वाली महिला की अनूठी सेवा

बादलों से घिरी घाटियों के पीछे से निकलकर हर सुबह जब सूरज की किरणें नगालैंड की पहाड़ी राजधानी कोहिमा में उजाला फैलाती हैं तो 'कोहिमा ऑर्फन ऐंड डेस्टिच्यूट होम' के दर्जनों बच्चे अपनी 'मां' 60 वर्षीया जापुतो अंगामी को घेर लेते हैं. पहले वे मौन प्रार्थना करते हैं. उसके बाद दिन भर खुशहाल रहने के लिए गीत गाते हैं.

जापुतो के इस अनाथाश्रम में 103 बच्चे हैं. इनमें उनका अपना सिर्फ एक है, बाकी परित्यक्त और अनाथ हैं जिन्हें वे खोज-खोज कर अपने आश्रम में ले आई हैं और यहां के अनूठे माहौल में पाल-पोस रही हैं. बच्चे उन्हें ही अपनी मां मानते हैं और अपने नाम के साथ उनका उपनाम भी लगाते हैं.

जापुतो की यह असाधारण कथा 15 साल पहले शुरू हुई थी. तब वे कोहिमा के सरकारी अस्पताल में नर्स थीं. उनके सैनिक पति की 1965 में मृत्यु हो गई. अस्पताल में उनकी जिंदगी एकरस हो गई थी.

लेकिन एक दिन जो घटना घटी उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी. अस्पताल में एक औरत एक सुंदर, स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद गुजर गई. दुखी बाप बच्चे को यह कहकर छोड़ गया कि वह इसकी देखभाल नहीं कर सकेगा. बच्चा अस्पताल में निराश्रित पड़ा था और जापुतो के दिमाग में तूफान उमड़ रहा था. तभी उन्होंने वह फैसला किया जिससे जिंदगी का मौजू ही बदल गया. वे बच्चे को घर ले आईं और उसका नाम दाइजेलि अंगामी रखा दिया. दाइजेलि के लालन-पालन में उन्हें खूब मजा आया, खासतौर पर उनकी बेटी निबाउवो को जो उस समय सिर्फ 10 साल की थी.

लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी. इस प्रदेश के जनजातीय समाज में कुंआरी मां को नफरत की नजर से तो नहीं देखा जाता लेकिन सामाजिक दबाव के कारण लड़कियां आमतौर पर शादी कर लेती हैं. मगर कुंआरी मां अपने बच्चे के पिता से शादी नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती. इस कारण ऐसे बच्चों का परित्याग कर दिया जाता है.

दाइजेलि को अपनाने के तीन महीने बाद

बच्चों के साथ जापुतो; और (बाएं) प्रार्थना करते बच्चे: एक बेमिसाल कोशिश

एक दिन जब जापुतो कोहिमा के घने जंगलों के पास से गुजर रही थीं तो उन्हें एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी. उन्होंने देखा कि एक लावारिस बच्चा बांस की टोकरी में पड़ा रो रहा था. वे उसे भी अपने घर ले आईं.

एक साल में वे ऐसे पांच बच्चे अपने घर ले आईं. निबाउवो जो, अब 25 साल की है, बताती है कि शुरू में इतने बच्चों की वजह से बोर होने का कोई मौका ही नहीं था. पर छठा बच्चा आया तो वह परेशान हो उठी. 11 साल की उम्र में ही वह बच्चों की देखभाल में जुटी रहती जबकि उसकी मां जापुतो अस्पताल में व्यस्त रहतीं. निबाउवो याद करती है, "यह काफी मजेदार काम था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

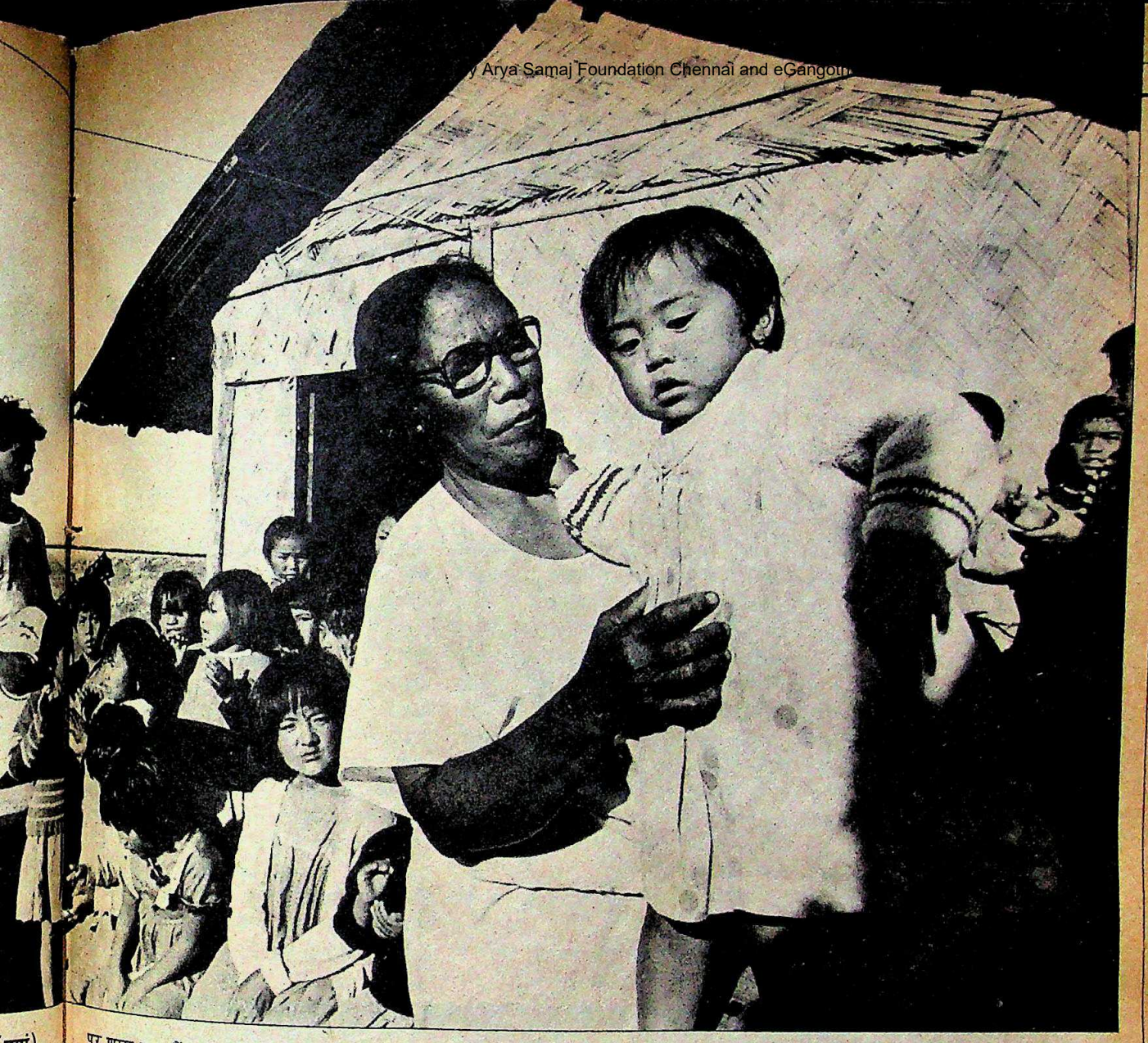

पर शाम तक मैं बुरी तरह थक जाती थी. मैं इसलिए भी परेशान हो उठती थी कि मां बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती थी."

बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई. 1982 तक जापुतो के पास 72 बच्चे आ गए और तीन बड़े-बड़े कमरों वाले उनके घर में तिल रखने की भी जगह नहीं बची. जब और जगह नहीं बची तो कुछ साल पहले उन्होंने सरकारी जमीन पर टिन-टप्पर और बांस से यह अनाथाश्रम बना लिया जिसमें बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशाला भी है.

हालांकि कोहिमा (आबादी: 1.25 लाख) कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है पर वहां बहुत कम ही लोगों को जापुतो के काम की जानकारी है, जानने की जरूरत भी नहीं समझते वे. ऐसे ही लोगों में वे मांएं भी हैं जिनके त्यागे हुए बच्चे इस आश्रम में पल रहे हैं. सिर्फ जापुतो ही जानती हैं कि वे कौन हैं. उनको उन्होंने तभी देखा था जब वे अपने बच्चे को छोड़ने आश्रम में आई थीं. इनमें से कई तो कुछ ही किलोमीटर दूर रहती हैं और अब समृद्ध घरों में ब्याही जा चुकी हैं. इनमें से गिनी-चुनी औरतें ही हैं जो जापुतो को आर्थिक मदद देने की परवाह करती हैं.

आश्रम की दिनचर्या पौ फटते ही शुरू हो जाती है. बिजली की घंटी सुबह चार बजे बच्चों को प्रार्थना और कसरत के लिए जगा देती है. नौ साल का बच्चा जॉन सबकी अगुआई करता है. उसने सेना के एक जवान से कसरत वगैरह सीखी है. नाश्ते में उन्हें सिर्फ एक कप चाय मिलती है. आश्रम इससे ज्यादा नाश्ते का खर्च नहीं उठा सकता. इसलिए दिन का खाना उन्हें काफी जल्दी परोस दिया जाता है. जब कभी कोई कुछ डबलरोटियां भेज देता है तो बच्चों के लिए नाश्ता किसी भोज की तरह हो जाता है.

साथ-साथ जीते हुए वे जिंदगी के तमाम उतार-चढ़ाव भी साथ-साथ झेलते हैं. इसकी एक मिसाल 1983 का क्रिसमस है. उस दिन बच्चे खुशी से झूम रहे थे. तभी जापुतो एक नवजात बच्ची को ले आईं. बच्चों से कहा गया कि वे हल्ला-गुल्ला न करें, क्योंकि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसे इलाज की जरूरत थी. शायद उसकी मां ने गर्भपात के लिए कड़वी दवाइयां खाई थी. बच्ची पर उन्हीं दवाओं का असर था. मौत से थोड़ी-सी लड़ाई लड़कर वह बच्ची गुजर गई और क्रिसमस की सारी खुशियां भूलकर पूरा आश्रम शोक में डूब गया.

कुछ बच्चों को अपने अतीत का पूरा एहसास भी है. लोग भी उन्हें अक्सर इसकी याद दिला ही देते हैं. अक्सर कोई-न-कोई बच्चा यह पूछ भी बैठता है कि उसका कोई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पिता क्यों नहीं है. जापुतो कहती हैं, "जब वे समझदार हो जाते हैं तो मैं उन्हें सच बता देती हूं. यही बेहतर है. वे साहस से आगे बढ़ना सीखें इसके लिए यह जरूरी है."

लेकिन उदासी की छाया बनी ही रहती है. 14 वर्षीय सेकोल ने हाल ही में एक कविता लिखी कि वह मां-बाप के प्यार का कितना भूखा है पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था. आश्रम की ही 16 वर्षीया लेस्ली ने एक कविता लिखी कि क्या स्वर्ग में बैठी उसकी मां कभी उसके बारे में भी सोचती है. लेस्ली की दो वर्ष पहले मृत्यु हो गई. आश्रम के सब बच्चे हर रोज इस कविता को गाते हैं.

लेकिन यह भावनात्मक शून्यता खासतौर पर बड़े बच्चों को जापुतो और निबाउवो के ज्यादा करीब ले आई है. हाल ही में जब जापुतो को मलेरिया हुआ तो कई बच्चों ने सारी रात उनके पास बैठने की जिद कर दी. वे इससे द्रवित हो उठी थीं, "मुझे अपने काम का पुरस्कार मिल गया."

मां और बेटी ने जो कुछ किया है, अपने बूते पर ही. हर कूड़ेदान के लिए 300 रुपए और बगीचों की हर कुर्सी पर 800 रुपए खर्च करने वाली नगालैंड सरकार इस आश्रम को महज 30,000 रुपए सालाना मदद देती है—यानी प्रति बच्चा 25 रुपए प्रति माह. केंद्रीय समाज कल्याण विभाग भी इतनी की ही मदद करता है.

इसलिए आश्रम का खर्च चलाने के लिए बड़े बच्चों को उलटे-सीधे काम करने पड़ते हैं. तकरीबन दर्जन भर बच्चों की तरह निथो और असाउ (दोनों 16 साल के) दिन भर एक गराज में काम करते हैं और रात में पढ़ते हैं. जापुतो कहती हैं, "मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा जब उन्हें इसी उम्र में इतनी जहमत उठानी पड़ रही है?

ईसाईबहुल नगालैंड में रविवार का दिन प्रार्थना और आराम या तफरीह का दिन होता है. लेकिन आश्रम के कुछ बच्चों के लिए रविवार का मतलब होता है सुबह-सुबह कोहिमा के विभिन्न बंगलों में जाना और बागवानी का काम करके चंद रुपए कमाना. उधर आश्रम में लड़कियां परंपरागत नगा शॉल बुनने बैठ जाती हैं.

जापुतो के पास पैसे की इतनी तंगी होती है कि अक्सर उनके लिए सब्जी जैसी जरूरी चीजें खरीदना भी मुहाल हो जाता है. ताजे साग की एक गठरी उठाये हाई स्कूल का छात्र 15 वर्षीय कुकुओलेतुओ कहता है, "हमें अक्सर ही इसे खाना पड़ता है. अब तो हमें इसका स्वाद भी अच्छा लगने लगा है."

इन मुश्किलों के बीच भी वे खुश तो रहते हैं लेकिन बदहाली की कई यादें भुला पाना भी मुश्किल होता है. कई बार तो पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की भी नौबत आई ताकि मृत बच्चों का दाह संस्कार किया जा सके.

पैसे के मामले में जापुतो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकतीं. उनकी तनख्वाह 500 रुपए प्रति माह है जिससे कुछ बच्चों के दूध का खर्च भी पूरा नहीं पड़ता. 1978 में उन्हें अपने चार तोले के सोने के गहने बेच देने पड़े थे. 1982 में निबाउवो के गहने भी बेचने पड़े. उस दिन को याद करके निबाउवो आज भी रो पड़ती है क्योंकि उसके पिता ने उन्हें बड़ी मेहनत से उसके लिए बनवाए थे.

समय बीतने के साथ-साथ जापुतो की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि उनके बाद बच्चों का क्या होगा. अब उनका सिर्फ एक ही सपना है कि सभी 103 बच्चे एक ही घर में बस जाएं. जगह की कमी के कारण काम-धंधे में लगे कुछ बड़े लड़कों को अलग किराए के दो कमरों में रहना पड़ता है. उन्हें उम्मीद है ये बड़े बच्चे आश्रम चलाने में सहयोग करेंगे. मिसाल के लिए 20 वर्षीय विटो नगालैंड पुलिस में सिपाही हो गया है. वह कुछ-कुछ महीनों बाद थोड़े-बहुत रुपए अनाथाश्रम को भेजता रहता है. कुछ दूसरे बच्चे बड़ी बेताबी से रोजगार की तलाश में हैं. उनमें दाइजिले भी है जिसे जापुतो सबसे पहले अपने घर लाई थीं.

निबाउवो की शादी एक डॉक्टर से हो गई है. इससे भी कुछ उम्मीदें बंधी हैं. उसे मालूम है कि देर-सवेर उसे और उसके पति को ही जिम्मेदारी संभालनी होगी. वह कहती है, "अब मुझे किसी सांसारिक सुख का कोई सपना नहीं और मुझे इसका कोई दुख भी नहीं."

—रमेश मेनन, कोहिमा में

नगा शॉल बुनती एक लड़की: घर चलाने की कसरत

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बंबई

रोग का रोना

स्तन कैंसर का बढ़ता कहर

डॉक्टरों, जनसंख्याविदों और समाज-शास्त्रियों के अलग-अलग क्षेत्र किसी विचित्र प्रक्रिया के तहत मानो एक विशेष बिंदु पर मिल जाते हैं. हाल के वर्षों में देश के दूसरे नगरों के मुकाबले बंबई की महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले अधिक पाए गए हैं. कैंसर चूंकि अमूमन व्यक्ति के आचार-व्यवहार और जीवन शैली की वजह से होता है, इसलिए इस रुझान से नई जानकारी मिलती है कि दूसरी जगहों के मुकाबले बंबई के रहन-सहन और खान-पान में किस कदर फर्क है. ताजा आंकड़ों के अनुसार बंबई में स्तन कैंसर के मामले 1964 में 12.4 प्रति लाख के मुकाबले 1984 में बढ़कर 14.4 प्रति लाख हो गए.

कम उम्र में विवाह और अधिक गर्भ-धारण जहां भारतीय महिलाओं में गर्भाशय कैंसर का बड़ा कारण रहा है, वहीं विवाह को अधिक समय तक टालते जाने और गर्भधारण का फासला बढ़ाने या स्वेच्छा से उससे बचने की शहरी औरतों की प्रवृत्ति उनमें स्तन कैंसर की ज्यादा संभावना पैदा करती दिखती है. इंडियन कैंसर सोसाइटी के निदेशक डॉ. डी.जे. जस्सावाला कहते हैं, "कैंसर शारीरिक रोग है इसलिए जैसी आपकी जीवन शैली होगी, वैसा ही आप पर इसका असर होगा."

बंबई का मामला खास तौर पर अनोखा है क्योंकि यहां देश भर में सबसे ज्यादा पारसी रहते हैं (शहर की 80 लाख आबादी में से 71,000 पारसी हैं). पारसियों में अधिक उम्र में शादी करने (या नहीं भी करने) का रिवाज है. उनके बच्चे भी कम ही होते हैं. स्तन कैंसर की शिकायत उनमें ज्यादा पाई जाती है. औसत भारतीय महिला की तुलना में उनमें इस बीमारी की संभावना दुगनी से ज्यादा है. स्तन कैंसर का संबंध ज्यादा उम्र से भी है. और दूसरे समुदायों के मुकाबले पारसी अधिक वर्षों तक जीते हैं. मसलन 1987 के अप्रैल और जून के बीच पारसियों में हुई कुल 243 मौतों में से सिर्फ आठ मृतक 40 वर्ष से कम उम्र के थे और 199 तो 60 से ऊपर के.

इस समुदाय की पत्रिका 'पारसियाना' के संपादक जहांगीर पटेल अफसोस जताते हैं, "पारसी समुदाय में आज भी जागृति बहुत कम है. अभी भी लोग ऐसी दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हैं कि सर्जन तो चीर-फाड़ कर डालेगा और एलोपैथ दवाई पर दवाई देता रहेगा. हमारे लोगों को अपने समुदाय में कैंसर की अधिक दर की जानकारी है, फिर भी इसके लिए सचेत होने का कोई प्रयास नहीं करता." अगर पारसियों की बात छोड़ दी जाए तो भी दूसरे शहरों के मुकाबले बंबई इस रोग के मामले में आगे है. जस्सावाला कहते हैं, "बंबई में पश्चिमीकरण बढ़ रहा है और इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा."

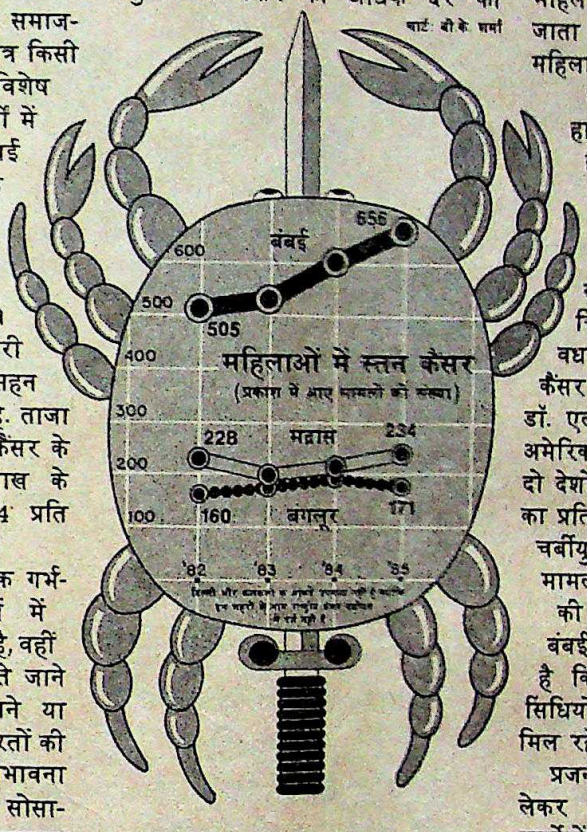

विवाह को अधिक समय तक टालने और गर्भ-धारण से बचने की प्रवृत्ति से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है

स्तन कैंसर के मामले यूरोपीय महिलाओं में भी बहुत अधिक पाए जाते हैं. वे एशियाई महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं, उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा है और उनका जीवन भी अधिक उन्मुक्त होता है. फिर अगर वे शादी करती भी हैं तो अधिक उम्र में. वे बच्चे भी कम पैदा करती हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा डिब्रूगढ़, चंडीगढ़ और तिरुअनंतपुरम में किए गए एक शुरुआती सर्वेक्षण से भी पता चलता है कि गरीब और निरक्षर महिलाओं में गर्भाशय कैंसर ज्यादा पाया जाता है जबकि शिक्षित और धनाढ्य महिलाओं में स्तन कैंसर ज्यादा होता है.

स्तन कैंसर के सही कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन ऐसे सबूत हैं कि चर्बीयुक्त भोजन, एसीटेट और कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजेन नामक एक ऐसा हार्मोन बनने में सहायता मिलती है जिससे स्तन में गांठें बन जाती हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में चल रही बंबई की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अवैतनिक सलाहकार डॉ. एल.डी. सिंघवी बताते हैं कि दक्षिण अमेरिका में रहन-सहन के निम्न स्तर वाले दो देशों पेराग्वे और उरुग्वे में स्तन कैंसर का प्रतिशत ज्यादा है क्योंकि वहां के लोग चर्बीयुक्त मांस ज्यादा खाते हैं. ऐसे मामलों में पारसियों में हुए अध्ययनों की पुष्टि हो चुकी है. इसके अलावा बंबई में अपुष्ट सर्वेक्षणों से पता चलता है कि स्तन कैंसर के ज्यादा मामले सिंधियों में हैं और अब गुजरातियों में भी मिल रहे हैं.

प्रजनन काल में (रजस्वला होने से लेकर रजोनिवृत्ति तक) महिलाओं के हार्मोनों में तेजी से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं. इसलिए डॉक्टरों का मानना है कि कम उम्र में प्रजनन और हार्मोनों की गतिविधि से स्तन कैंसर की संभावना घट जाती है. कुछ डॉक्टरों का यह भी मानना है कि 18 वर्ष की उम्र में बच्चा होने से स्तन कैंसर का खतरा 70 फीसदी तक कम हो जाता है.

बहरहाल, बंबई में स्तन कैंसर के अधिक मामलों के कारण डॉक्टरों का मानना है कि महिलाओं के पास इसके दो ही उपाय हैं. एक तो मासिक धर्म के बाद परीक्षण करवाना और दूसरे किसी तरह की असामान्यता का जल्दी से जल्दी इलाज कराना. इस तरह उनके स्तन ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनके जीवन की सुरक्षा भी हो सकेगी. कैंसर का पता लगाने के अब अत्याधुनिक उपकरण आ गए हैं. जेरोमैम्मोग्राम्स से अब वह सब पता चल सकता है जो हथेली से पता नहीं चलता. मैसोक्टोमी जल्द ही अतीत की बात बन जाएगी.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

सनकी हत्यारे की शिनाख्त

ऑटोरिक्शा चालक द्वारा की गई छह हत्याओं का सुराग मिला

मद्रास शहर के पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) के.के. राजशेखरन नायर के पास लोगों की गुम होने की शिकायतें आती ही रहती थीं. लेकिन उनकी छठी इंद्रिय संकेत दे रही थी कि यह मामला कुछ अलग है. उस तपती दोपहर में उनके सामने बैठी महिला सुबकते हुए उन्हें बता रही थी कि उसका पति संपत, भाई मोहन और उनका दोस्त गोविंदराज महीने भर से लापता हैं. ये तीनों शाम की सैर को दक्षिण मद्रास के इलाके तिरुवनमियूर जाने के लिए घर से निकले और लौटे नहीं.

नायर ने यह मामला इस निर्देश के साथ अपराध शाखा को सौंप दिया कि मामले की तह तक पहुंचा जाए. दक्षिण मद्रास शहर पुलिस की सहायता लेकर अपराध शाखा के जासूस तिरुवनमियूर के इर्दगिर्द चक्कर लगाते रहे. आखिर में एक ताजा बनी झोंपड़ी के फर्श की खुदाई करने पर उन्हें तीनों लापता व्यक्तियों की लाशें मिल गईं.

पता चला कि एक पागल हत्यारा शहर में खुला घूम रहा है. वह तौलिये से गला घोंटकर लोगों को मार डालता और उनके शव दफना देता. पुलिस ने जल्दी ही हत्यारे की शिनाख्त कर ली. यह 33 साल का टी. गौरीशंकर उर्फ 'ऑटो शंकर' था, जो तिरुवनमियूर में ऑटोरिक्शा चलाने के अलावा एक अवैध शराबघर भी चलाता था. पुलिस का मानना है कि यह दुबला-पतला सुस्त-सा आदमी पिछले सात महीनों में कम से कम छह व्यक्तियों की हत्या कर चुका है. इनमें पांच मर्द और एक औरत थी. पुलिस तिरुवनमियूर में कुछ स्थानों से चार पुरुषों और एक महिला के कंकाल खोदकर निकाल चुकी है. चारों पुरुषों के शवों की पहचान हो चुकी है पर महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई. सभी को गला घोंटकर मारा गया था.

शंकर और उसके दो साथियों को हिरासत में लेने के बाद ही पुलिस ने ये लाशें मिलने की घोषणा की लेकिन इन अपराधियों से पूछताछ के बाद जो कहानी बनी वह चकरानें वाली थी. शंकर दिन में सीधे-सादे आदमी की तरह ऑटोरिक्शा चलाता पर रात को जब उसके सिर पर खून सवार हो

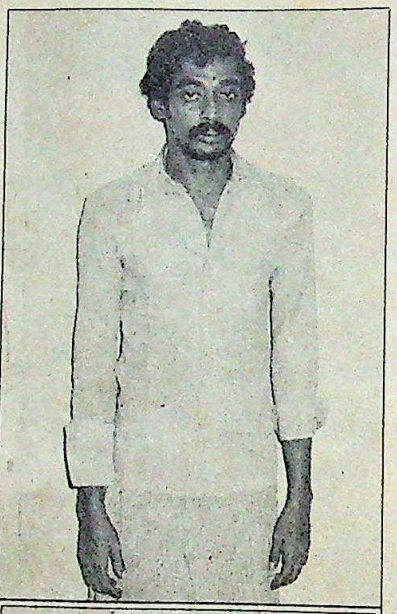

हत्यारा टी. गौरीशंकर ऑटोरिक्शा चलाने के अलावा अवैध शराबघर और वेश्यालय भी चलाता था. उसकी गिरफ्तारी के बाद एक इंस्पेक्टर और दारोगा को मुअत्तल कर दिया गया

जाता तो कई लोगों की हत्याएं कर देता.

तिरुवनमियूर में शंकर का अवैध शराबघर उसकी सनक का केंद्र था. शंकर यहां के लोगों की पसंदीदा शराब अरक सप्लाई किया करता. वह एक किस्म का माफिया सरगना बन गया था. दक्षिण मद्रास पुलिस के साथ भी उसके संपर्क बन गए थे. हत्याओं की शुरुआत उसने इसी शराबघर से की. उसका पहला शिकार उसकी उपपत्नी ललिता थी, जिसे उसने पिछले साल अक्तूबर में गला घोंटकर मार डाला. शंकर को शक था कि वह उससे ज्यादा उसके सहयोगी चुड़ालई को चाहने लगी थी. एक शाम शंकर ने उसका गला घोंट दिया और लाश अपने घर के नजदीक खुले मैदान में गाड़ दी. फिर उसी जगह पर एक कच्ची झोंपड़ी बनवा कर बीस रु. महीने किराए पर उठा दी. इसी जगह पर उसने और भी कई झोंपड़ियां बनवाईं. तब तक वह चुड़ालई की भी हत्या कर चुका था.

शंकर का अगला शिकार बना ऑटोरिक्शा चालक रवि जो शंकर और चुड़ालई दोनों का दोस्त था. एक बार शराब पीते-पीते रवि शंकर से पूछ बैठा कि चुड़ालई कहां गायब हो गया. इतना सुनते ही शंकर ने रवि की गरदन के गिर्द तौलिया लपेटा और उसका भी काम तमाम कर दिया. इसके बाद संपत, मोहन और गोविंदराज उसके शिकार बने.

इन हत्याओं की सूची और भी लंबी हो सकती है. पुलिस अब शंकर की दूसरी पत्नी 18 वर्षीया गीतासुंदरी की मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है. 1983 में उसकी मृत्यु 'संदिग्ध हालात' में जलने से हुई थी. यह भी पता लगा कि शंकर की दो पत्नियां हैं. उसकी पहली पत्नी 30 वर्षीया जगदीश्वरी और उसके चार बच्चे मद्रास में ही अलग मकान में रहते हैं. इसी आधार पर नायर ने इस इलाके में संदिग्ध हालात में हुई मौतों के दर्ज मामलों की पड़ताल के आदेश दिए हैं. नायर बताते हैं, "अगले महीने तक हम शंकर और उसके गिरोह के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र दाखिल कर देंगे."

शंकर मूलतः तमिलनाडु के उत्तरी आर्कोट जिले के वेल्लूर के नजदीक कंगेनल्लूर का रहने वाला है. ऑटोरिक्शा चलाना शुरू करने से पहले वह मद्रास में छोटे-मोटे काम करके गुजारा करता रहा. लेकिन उसकी आमदनी नाजायज धंधों से ही थी. इस आमदनी से उसने झोंपड़पट्टी कॉलोनी के बीचोबीच एक आलीशान घर भी बना लिया. इसके एक हिस्से में वह वेश्यालय भी चलाता था. उसने पुलिस विभाग में अपने 'संरक्षक' भी बना रखे थे जो उसे गिरफ्तारी से बचाए रखते थे.

शंकर की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद चिंगलपुट पूर्व के पुलिस उप-निरीक्षक का तबादला कर दिया गया और एक इंस्पेक्टर तथा एक सब-इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया. इनके 'ऑटो शंकर' के साथ संबंध थे. अब हालांकि शंकर जेल के सीखचों के पीछे बंद है लेकिन ऑटोरिक्शा से सफर करने वाले लोग हर चालक को संदेह की नजर से देखते हैं— खासकर यदि उसने अपनी गरदन के गिर्द तौलिया लपेट रखा हो.

—एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एअर इंडिया

महाराजा की सेवा में

प्रभात पंजियार

दौरे से राजीव की वापसी: उड़ानों पर विवाद

किसी पूर्व पायलट के लिए यह भारी विडंबना ही है कि उसकी बार-बार होती उड़ानों पर टंटा खड़ा हो. पिछले पखवाड़े जब राजीव अपनी 22वीं विदेश यात्रा से लौटे तो उन पर हमलों की बौछार और तेज हो गई. विवाद मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि उनकी उड़ान से एअर इंडिया की बाकी उड़ानें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं. उसे न सिर्फ अपनी अनेक सामान्य उड़ानों को रद्द करना पड़ा था बल्कि यात्रियों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए दूसरी विमानसेवाओं से विमान भी किराए पर लेने पड़े. भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने आरोप लगाया, "दुनिया के नागरिक विमानन हलकों में एअर इंडिया की बदनामी हो रही है."

इस बार राजीव ने जंबो के बदले एअरबस को चुना. पर आलोचना फिर भी हुई, खासकर इसलिए कि राष्ट्रपति भी अपनी मास्को यात्रा के लिए एअर इंडिया का एक जंबो विमान ले गए थे. इस बदनामी को रोकने के लिए एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन जेतली ने राजीव के लौटने पर एक प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई. सरकार के निर्देश पर उन्होंने वीवीआईपी उड़ानों के सिलसिले में एअर इंडिया की समस्याओं को मामूली बताया. उन्होंने कहा, "हमें सिर्फ कुछ उड़ानों का समय बदलना पड़ा. एअर इंडिया को चार्टर्ड उड़ानों से तो मुनाफा होता है." प्रेस कान्फ्रेंस में रद्द उड़ानों का यह ब्यौरा दिया गया:

► 7 और 27 जुलाई के बीच ए-310 एअरबस की 13 उड़ानें रद्द की गईं—चार घरेलू और बाकी खाड़ी देशों की.

► 10 और 22 जुलाई के बीच ए-310 की मुख्यत: खाड़ी देशों को जाने वाली 12 उड़ानों के समय में फेरबदल किया गया जिससे पांच घंटे तक की देरी हुई.

► 9 से 22 जुलाई के बीच मस्कट और जेद्दाह के लिए इंडियन एअरलाइंस के ए-300 विमान की छह उड़ानें हुईं. इन उड़ानों के चालक दल में एअर इंडिया के और बाकी कर्मचारियों में इंडियन एअरलाइंस के लोग थे.

► बोइंग-747 की 2 से 7 जुलाई के बीच छह और 14 से 16 जुलाई के बीच पांच उड़ानें रद्द की गईं. ये उड़ानें सिंगापुर, फ्रैंकफुर्त, टोक्यो आदि की थीं.

► बोइंग-747 को न्यूयॉर्क की एक उड़ान को लंदन तक कर दिया गया और यात्रियों को दूसरी विमानसेवाओं के विमानों से भेजा गया. बाद में यह विमान पेरिस से एअर इंडिया की सामान्य उड़ान के तौर पर बंबई लौटा. लंदन से वापसी उड़ान में यात्रियों को लाने के लिए एअर इंडिया ने 'इजिप्ट एअर' का एक विमान किराए पर लिया. इसी तरह न्यूयॉर्क से लंदन आने वाले यात्रियों को भी दूसरी विमानसेवाओं के जरिये पहुंचाया गया.

एअर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की ज्यादा नाराजगी इस विमानसेवा की छवि बिगड़ने को लेकर है. कर्मचारी तो अंतिम क्षण में उड़ानें रद्द हो जाने या उनका समय बदल जाने से एअर इंडिया की होती बदनामी से भी दुखी हैं. असल में क्षुब्ध यात्रियों का गुस्सा तो इन कर्मचारियों को ही झेलना पड़ता है.

एअर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक वीवीआईपी उड़ान के लिए चार्टर्ड विमान दौरे के पहले और उसके बाद कुल मिलाकर करीब 10 दिन उड़ान नहीं भर पाता. और फिर दौरे में खर्च हुए दिन इससे अलग हैं. दरअसल दौरे पर जाने से छह दिन पहले विमान को चमकाने-दमकाने और सुरक्षा जांच के लिए सामान्य सेवा से हटा लिया जाता है और फिर लौटने के बाद चार दिन उसकी सीट की व्यवस्था सामान्य बनाने में लग जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री के 22 विदेशी दौरों में एक विमान कम-से-कम 220 दिन खाली रहा.

समस्या यह है कि एअर इंडिया के पास विमानों की तंगी है. उसके पास 10 बोइंग-747 विमान (377 सीटों वाले), छह 310 एअरबसें (198 सीटों वाली) और तीन ए-300 विमान (234 सीटों वाले) हैं. वैसे, इस साल के अंत तक उसे बोइंग-कोंबीज भी मिल जाएंगे.

एअर इंडिया के पायलटों की यूनियन 'इंडियन पायलट्स गिल्ड' के महासचिव कैप्टन ए. मुकर्जी कहते हैं, "किसी भी सक्षम एअरलाइन के सामने कुछ विमानों के हटा लेने से उड़ानों के समय में रद्दोबदल की बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए." वीवीआईपी उड़ानों के बारे में जानकारी बहुत पहले मिल जाती है. इसलिए व्यापक रद्दोबदल करने का अर्थ है योजना का अभाव.

1987 में एक सरकारी समिति ने वीवीआईपी बेड़े के लिए विमानों का मूल्यांकन किया था. रूस ने इसके लिए एक इल्यूशिन-62 विमान देने की पेशकश की थी और बोइंग-707 भी विचाराधीन था. लेकिन लालफीताशाही और बोझिल कार्यप्रणाली के चलते कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया. जब तक यह फैसला नहीं होता एअर इंडिया के महाराजा को भारत के 'असली महाराजा' की बार-बार की यात्राओं का जोखिम उठाना ही पड़ेगा.

—एम. रहमान और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय विज्ञान

आशा और निराशा की आंखमिचौनी

इसमें लागत तो बहुत है पर हासिल कम. प्रमुख संवाददाता राज चेंगप्पा और वरिष्ठ संवाददाता अमरनाथ के. मेनन ने भारत के विज्ञान कार्यक्रम की खामियों के बारे में कई वैज्ञानिकों से बातचीत की.

कंट्रोल रूम में कंप्यूटर का हल्का-सा कंपन प्रक्षेपण मंच पर रखे पांच चरणों वाले रॉकेट को हरकत में ला देता है. इसकी निकास नलियों से दोधारी लपटें निकलती हैं. और यान एक गरज के साथ ऊपर उठता है, अंतरिक्ष की बुलंदियां छू लेने के लिए. लेकिन 54 सेकंड बाद ही आकाश में सन्नाटा छा जाता है और सर्पिल आकार में धुआं नीचे की ओर आता दिखाई पड़ता है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यू.आर. राव 16 महीनों में दूसरी बार घोषणा करते हैं, "बेहद दुख से मुझे यह बताना

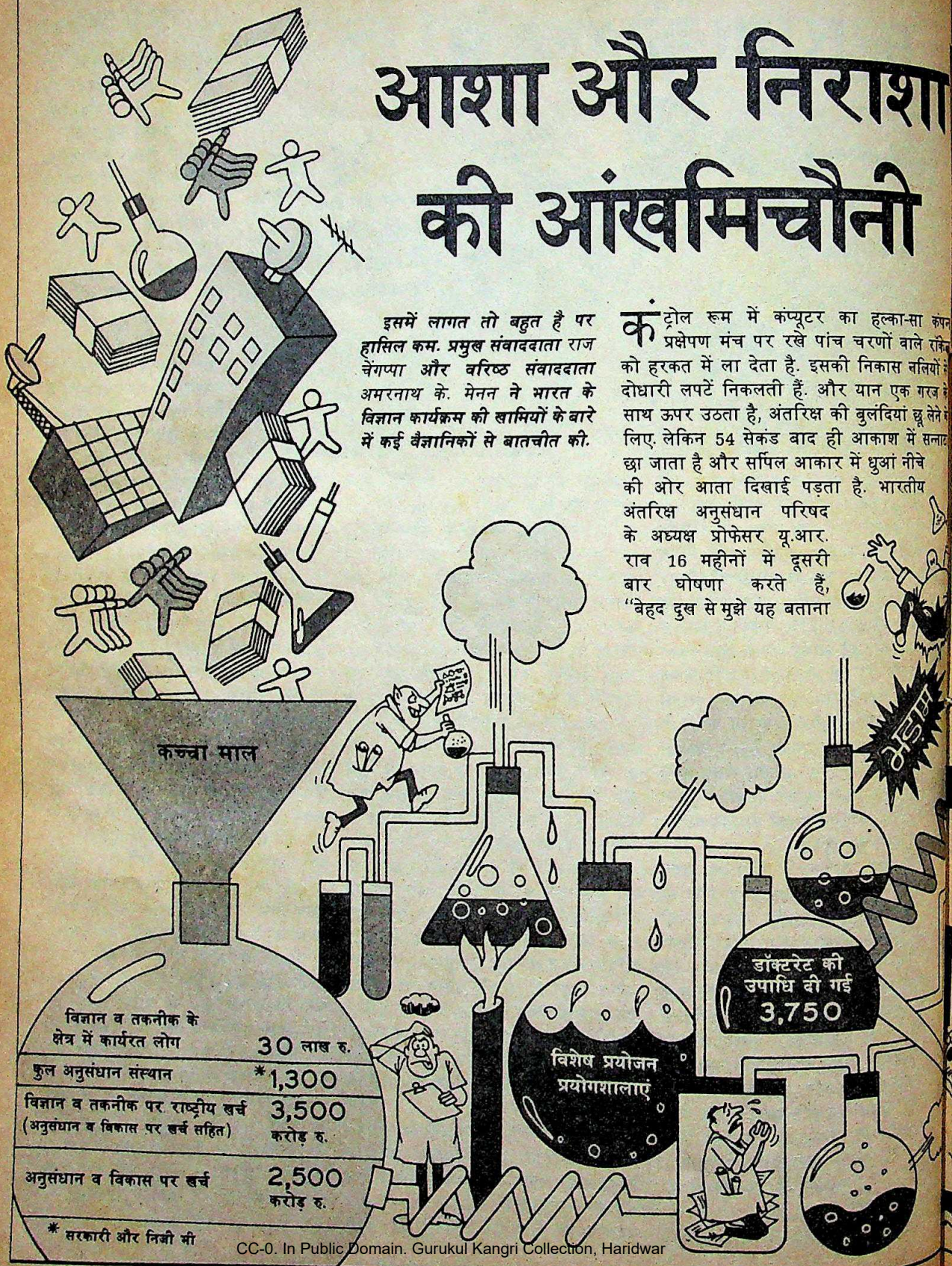

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पड़ रहा है कि हमारा यह मिशन असफल रहा."

संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (एएसएलवी) की दूसरी बार नाकामी से अकेले अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही दुखी नहीं हैं. बंगलूर की राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला के निदेशक प्रो. रौद्दम नरसिंह कहते हैं, "भारतीय विज्ञान के प्रति लोगों का नजरिया आशा और निराशा के बीच झूलता रहता है."

वैज्ञानिक खुद ही अपने सबसे मुखर आलोचक बन गए हैं. प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो.सी.एन.आर. राव ने बंगलूर में कहा, "बहुत दुख के साथ यह मानना पड़ रहा है कि हमारे ढेर सारे वैज्ञानिकों में कुछ ही असाधारण प्रतिभाएं हैं. वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आ रहे लोग उत्कृष्ट कोटि के नहीं हैं. तकनीकी क्षेत्र में हमारी प्रतिभाएं और क्षमताएं विकसित नहीं हुई हैं."

निस्संदेह भारत में विज्ञान के विकास में जितना निवेश हो रहा है, वह किसी भी विकासशील देश के लिए गर्व का विषय हो सकता है. यहां तीस लाख से भी ज्यादा लोग विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. वैज्ञानिक कार्यों में लगे लोगों की संख्या के लिहाज से दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है. यहां सरकारी सहायता से चल रहे लगभग 1300 अनुसंधान संस्थान हैं, जो परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रतिरक्षा, वैमानिकी, कृषि, वन,

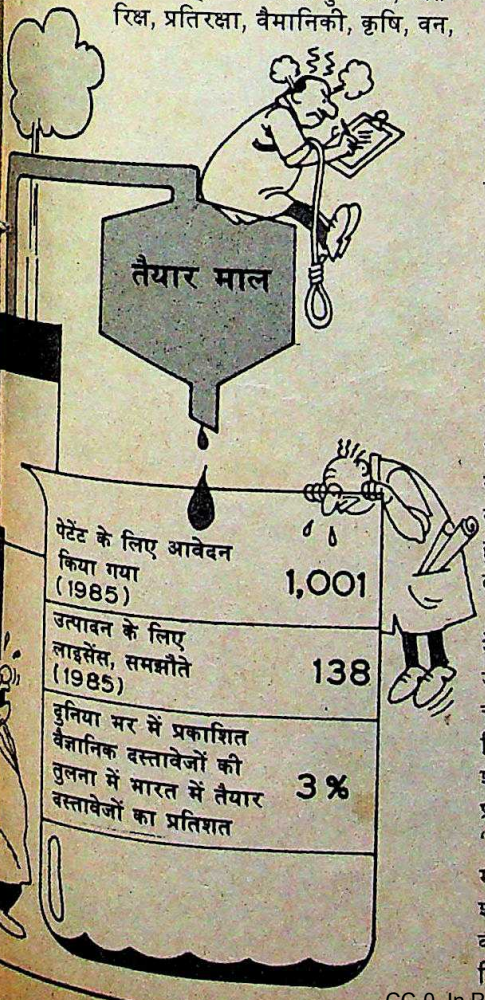

उड़ान के कुछ पल बाद ही एएसएलवी नाकाम हो गया

पीटीआई

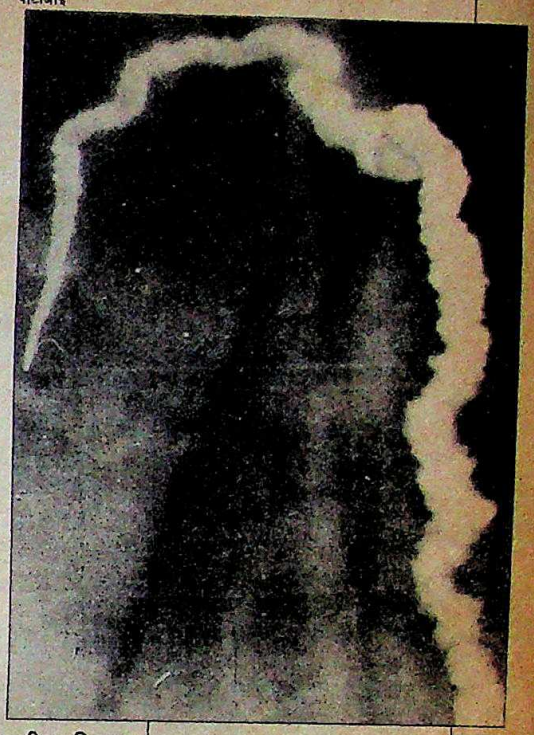

इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य जैसे अनेक क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान कर रहे हैं. कुल मिलाकर इन संस्थानों पर 3,500 करोड़ रु. का खर्च आता है. और सबसे बड़ी बात यह कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय प्रधानमंत्री के मातहत होने से देश के वैज्ञानिकों की सीधी उन तक पहुंच भी है.

लेकिन भारत परमाणु और अंतरिक्ष दोनों क्लबों का सदस्य होने के बावजूद हर जगह पिछड़ा हुआ ही दिखता है. तकनीकी मिशन के प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं, "विज्ञान में ढेर सारा पैसा लगाने के बदले हमें ज्यादा नतीजे भी मिलने चाहिएं. घर में सोने की खान होने के बावजूद हमारे यहां हताशा का अंबार है और उपलब्धियां बहुत कम." बंगलूर में भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रो. ए.के.एन. रेड्डी मूल समस्या पर नब्ज रखते हैं, "भारत में विज्ञान के लक्ष्य यहां के गांवों में रह रहे लोगों की जरूरतों और हालात को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि पश्चिम की धारणाओं के मुताबिक निर्धारित होते हैं. इसी विरोधाभास के चलते तमाम शोध बेमतलब हो जाते हैं."

भारतीय विज्ञान की जर्जरता का बड़ा प्रतीक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) है. 42 अनुसंधान प्रयोगशालाओं वाली यह संस्था हर साल केंद्रीय खजाने से 200 करोड़ रु. डकारती है. इसके कामकाज की समीक्षा करते हुए पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति ने कहा था, "परिषद की व्यवस्था से अनियोजित विकास के साथ-साथ अधूरे काम का भी आभास मिलता है. कोई स्पष्ट दिशाबोध तो है ही नहीं. परिषद की बड़ी नाकामी शायद यह है कि यह प्रयोगशाला में हासिल हुए वैज्ञानिक नतीजों को औद्योगिक उत्पादन की तकनीकों में नहीं बदल सकी."

यह आलोचना परिषद पर ही नहीं, बल्कि देशभर में फैले अधिकांश वैज्ञानिक संस्थानों पर भी खरी उतरती है. इनमें हर कोई अब मानो सफेद हाथी बन चुका है. हरेक में नौकरशाही की भरमार हो गई है. दिशाहीनता का शिकार होने के अलावा वे अपना शोध व्यावहारिक प्रयोग में लाने में नाकाम रहे हैं. प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं, "हम एक साथ कई नावों पर सवार हैं. सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के बजाय हमने अपने शोध और पैसे को हर क्षेत्र में लगा दिया है. व्यावहारिक विज्ञान को मूलभूत शोध जितनी अहमियत नहीं दी जाती."

■ **"बहुत दुख के साथ मानना पड़ रहा है कि हमारे ढेर सारे वैज्ञानिकों में कुछ ही असाधारण प्रतिभाएं हैं. वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आ रहे लोग उत्कृष्ट कोटि के नहीं"**

प्रो. सी.एन.आर. राव
अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद

■ **"विज्ञान में ढेर सारा पैसा लगाने के बदले हमें ज्यादा नतीजे भी मिलने चाहिए. घर में सोने की खान होने के बावजूद हमारी उपलब्धियां बहुत कम हैं"**

सैम पित्रोदा
प्रमुख, तकनीकी मिशन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ "भारत में विज्ञान के लक्ष्य यहां के गांवों में रह रहे लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि पश्चिमी अवधारणाओं के मुताबिक निर्धारित होते हैं"

प्रो. ए.के.एन. रेड्डी
भारतीय विज्ञान संस्थान

■ "हम एक साथ कई नावों पर सवार हैं. सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के बजाय हमने अपने शोध और पैसे को अनेक क्षेत्रों में लगा दिया है"

एम.एस. स्वामीनाथन
प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक

■ "पिछले कुछ साल में भारत ने जिस तरह कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, बहुत ही कम विकासशील देश उस स्तर पर पहुंच पाए हैं"

एम.आर. श्रीनिवासन
अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग

शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन और पेटेंट के लिए दी गई अर्जियों की दो अहम कसौटियों पर जब भारतीय वैज्ञानिकों को आंका जाता है तो वे फिसड्डी साबित होते हैं. भारतीय वैज्ञानिकों के दो-तिहाई शोधपत्र देश की करीब 500 पत्रिकाओं में छपते हैं. अनुसंधान परिषद के सूचना और प्रचार निदेशालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारतीय पत्रिकाओं में छपे शोधपत्रों के संदर्भ स्रोत बहुत घटिया स्तर के होते हैं. विदेशी प्रकाशनों में तो इन पत्रिकाओं का जिक्र शायद ही कभी होता है. इस अध्ययन के मुताबिक, "भारतीय पत्रिकाएं रद्दी की टोकरी मानी जाती हैं, सूचना का स्रोत नहीं." कुल मिलाकर देश को हर प्रकाशित शोधपत्र पर पांच लाख रु. खर्च करने पड़ते हैं जो कि वाकई एक महंगी कसरत है.

उधर उत्पादन के मोर्चे पर देखें तो पेटेंट महा-नियंत्रक के पास हालांकि हर साल औसत 3,000 पेटेंट दर्ज कराए जाते हैं पर आंकड़े सच्ची बात जाहिर नहीं करते. इनमें एक तिहाई या करीब 1000 पेटेंट ही भारतीयों के होते हैं. मसलन परिषद की कोई भी प्रयोगशाला साल में मुश्किल से मात्र एक विधि विकसित कर पाती है.

भारतीय विज्ञान में कोई दम न हो, ऐसी बात नहीं. 60 के दशक में वैज्ञानिकों ने कृषि में हरित क्रांति लाकर अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना दिया था. इसके बाद श्वेत क्रांति का दौर चला और ऑपरेशन फ्लड के जरिये दूध की नदियां बहा दी गईं. इस बीच वैज्ञानिकों ने उन क्षेत्रों में भी अपनी काबिलियत साबित कर दी जिनमें आम तौर पर जानकारियां कहीं और से नहीं मिल पातीं. इससे भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया और उसने अत्याधुनिक उपग्रह व साधारण उपग्रह प्रक्षेपक बनाने की क्षमता हासिल कर ली. मूलभूत शोध में भी भारत का योगदान बहुत से क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण है. परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एम.आर. श्रीनिवासन कहते भी हैं, "पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल की है, बहुत ही कम विकासशील देश उस स्तर पर पहुंच पाए हैं."

पर अतीत की यह चमक भी अब धुंधला रही है. आज भारतीय विज्ञान समस्याओं से ग्रस्त हो गया है. जिन क्षेत्रों में नौजवानों की सृजनात्मक प्रतिभा की जरूरत है, वहां बुजुर्गशाही का जबरदस्त बोलबाला हो गया है. प्रयोगशालाओं के अधिकांश वरिष्ठ वैज्ञानिकों और प्रमुखों की औसत उम्र 50 साल से ज्यादा और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की करीब 38 साल है. बंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के जाने-माने अणुजीव विज्ञानी प्रो आबिद सिद्दीकी कहते हैं, "विदेशों में ज्यादातर निदेशक 35 साल की उम्र में नियुक्त किए जाते हैं पर हमारे यहां सीनियर लोगों के चुनाव में स्फूर्ति और उत्साह की अनदेखी करके पके बालों वाली प्रतिभा को ही जगह दी जाती है. यही हमारी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है."

अब होमी भाभा और विक्रम साराभाई सरीखे दूरदृष्टि वाले और उत्साहपूर्ण लोगों के दिन लद गए. अब तो वैज्ञानिकों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ नहीं आ गए हैं (जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग में

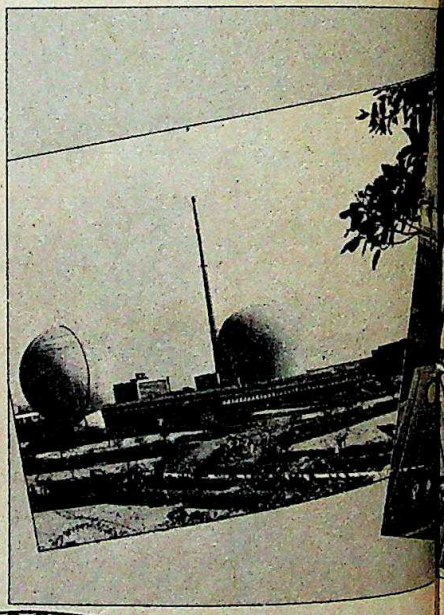

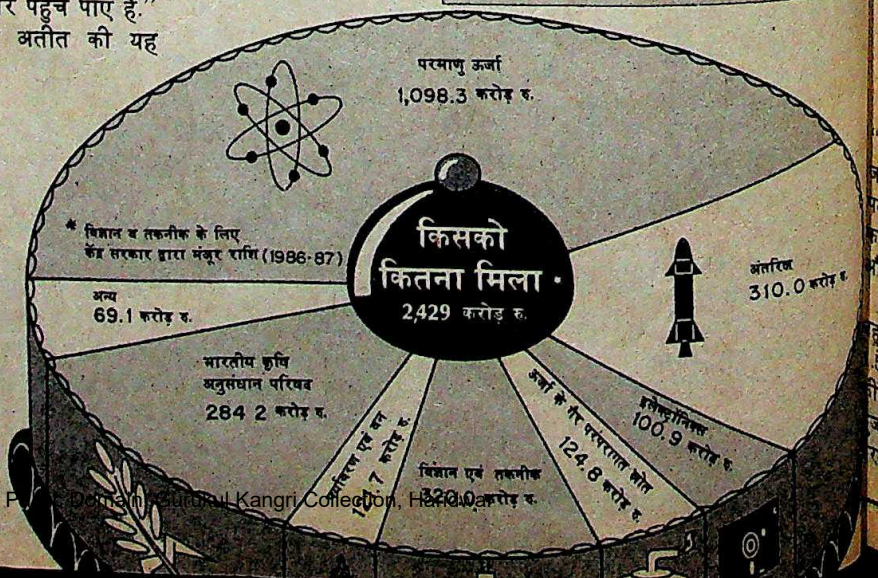

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीनिवासन और डॉ. पी.के. आयंगर के बीच हाल ही में चली ओहदे की लड़ाई) बल्कि वैज्ञानिक संस्थानों का आकार इस कदर बढ़ गया है कि उनका कारगर प्रबंध ही नहीं हो पाता. बहुत से वैज्ञानिकों की यहां तक शिकायत है कि उनके अगुआओं को चापलूस ही पसंद है. टाटा इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता सुनील मुखी कहते हैं, "आमतौर पर प्रतिभा नहीं, वफादारी देखी जाती है. नतीजा यह है कि घटिया लोग आगे आ जाते हैं. आलोचना की आजादी न होना विज्ञान के लिए घातक बन जाता है."

भर्ती और तरक्की की नीतियों ने तो ज्यादा बिगाड़ किया है. पैसे से चल रहे संस्थानों में अगले वेतनमान में तरक्की का आधार अमूमन वरिष्ठता होती है, उसमें काबिलियत कभी-कभार ही देखी जाती है. नौजवान वैज्ञानिकों के लिए तो यह बेहद कुंठाजनक बात है. अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला में शोधार्थी, अमिताभ सेनगुप्त कहते हैं, "सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें कोई बड़ी जवाबदेही नहीं है. अगर कोई काम करता है तो उसे पर्याप्त फायदा नहीं मिलता और अगर कोई नहीं करता तो उसे कोई सजा नहीं मिलती. यह व्यवस्था औसत दर्जे के वैज्ञानिक पैदा करती है."

समस्या पैसे की कमी की नहीं है. इसकी तो शिकायत है क्योंकि सरकार हर शोधार्थी पर सालाना 2.5 लाख रु. खर्च करती है. लेकिन छोटे-से उपकरण की खरीद के लिए भी लालफीताशाही के जिस चक्र से गुजरना पड़ता है उससे बेमतलब की देरी होती है. दरअसल अधिकांश शोधार्थी बताते हैं कि जो काम विदेश में एक साल में होता है, अपने यहां उसे तीन साल लग जाते हैं. भाभा परमाणु शोध केंद्र में भौतिक विज्ञान विभाग में प्रमुख डॉ. आर. चिदंबरम कहते हैं, "भारत में शोध की गति काफी धीमी है."

ज्यादातर वैज्ञानिक भारतीयों के एक टीम के रूप में काम न कर पाने की ओर ध्यान दिलाते हैं. बंबई विश्वविद्यालय में रसायन प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर एम.एम. शर्मा कहते हैं, "हम कभी एक होकर काम नहीं कर सकते. हर कोई अपनी ढपली, अपना राग अलापता है." नौजवान वैज्ञानिकों को शिकायत है कि उन्हें अपनी परियोजनाएं चुनने की बहुत कम आजादी मिलती है. प्रो. राव स्वीकार करते हैं, "हम युवा वैज्ञानिकों को काम करने की ज्यादा आजादी देने और उनसे बेहतर नतीजे हासिल करने के बजाय उनकी गरदन पर सवार रहते हैं."

प्रयोगशालाओं को इतना पैसा मिलता है कि बरबादी रोजमर्रा की चीज बन गई है. देश के वित्तीय मामलों पर नजर रखने वाले लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे अनेक उदाहरण गिनाए हैं. मसलन कलकत्ता के बोस संस्थान ने 1979 में 11.84 करोड़ रु. में एक स्पेक्ट्रोमीटर खरीदा. सात साल तक जंग खाते रहने के बाद उसे 1986 में जाकर ही स्थापित किया गया.

अभी दो महीने पहले ही सीएजी ने देश की आंखों के तारे इस परमाणु ऊर्जा विभाग की कलई खोली. इसके सबसे गौरवपूर्ण तूतीकोरिन गुरुजल संयंत्र के लेखा परीक्षण के दौरान सीएजी ने पाया कि संयंत्र को लगाने में न केवल तीन साल की देरी हुई बल्कि पिछले आठ वर्षों से यह अपनी क्षमता का बमुश्किल 20 फीसदी उत्पादन कर रहा था. इस तरह संयंत्र को उत्पादन में करीब 123.97 करोड़ रु. घाटा हुआ.

हालांकि भारतीय विज्ञान और तकनीक की मौलिक समस्या यह है कि अनुसंधान के नतीजों का

■ **"हमारे यहां सीनियर लोगों के चुनाव में स्फूर्ति और उत्साह की अनदेखी करके पके बालों वाली प्रतिभा को ही जगह दी जाती है. यही हमारी सबसे कमजोर कड़ी है"**

प्रो. आबिद सिद्दीकी
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च

■ **"अगर कोई काम करता है तो उसे पर्याप्त फायदा नहीं मिलता और कोई नहीं करता, उसे सजा नहीं मिलती. यह व्यवस्था औसत दर्जे के वैज्ञानिक पैदा करती है"**

अमिताभ सेनगुप्त
वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

■ **"हम कभी एक होकर काम नहीं कर सकते. हर कोई अपनी ढपली, अपना राग अलापता है... हम युवा वैज्ञानिकों की गरदन पर सवार रहते हैं"**

प्रो. एम.एम. शर्मा
रसायन प्रौद्योगिकी विभाग, बंबई विश्वविद्यालय

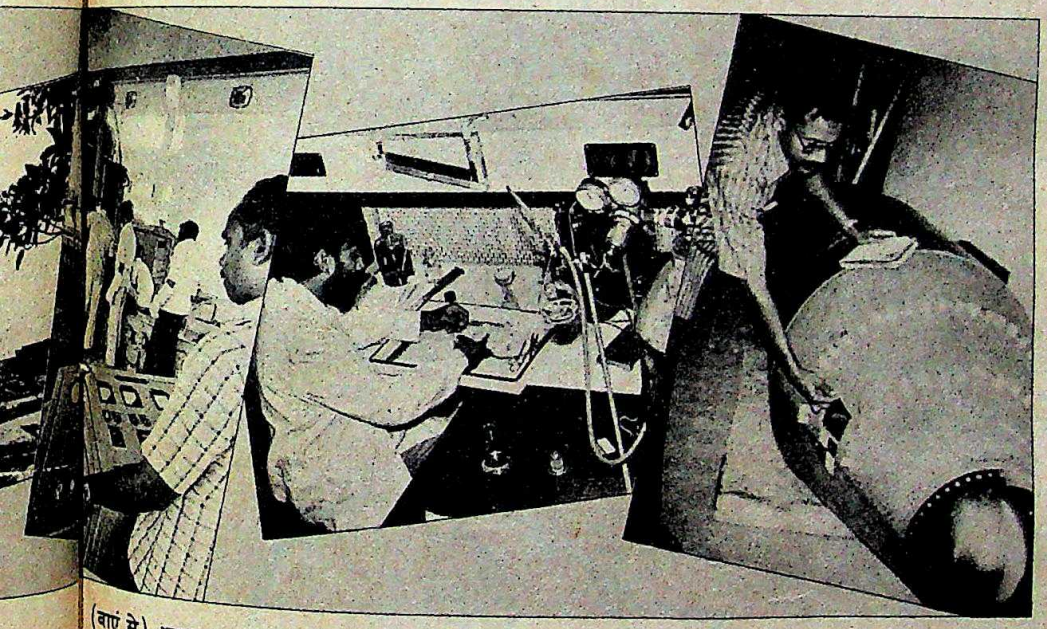

(बाएं से) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र; बैटल टैंक परीक्षण; सीएसआईआर विषविज्ञानी द्वारा परीक्षण और एएसएलवी के सिरे की प्रतिकृति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ "व्यावहारिक विज्ञान का उद्योग से सीधा रिश्ता बने इसकी अब तक कोशिश नहीं हुई. सीएसआईआर समाधान तो खोजती रही पर समस्याओं से उनका रिश्ता नहीं के बराबर रहा"

राजा रमन्ना
पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग

यथेष्ट उपयोग नहीं होता. प्रयोगशालाओं में जितने अनुसंधान कार्यक्रम चलते हैं उनमें शायद एक तिहाई ही ऐसे होंगे जिनके परिणामों के उपयोग की पहले से व्यवस्था होती है. परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजा रमन्ना कहते हैं, "व्यावहारिक विज्ञान का उद्योग से सीधा रिश्ता बने इसकी अब तक किसी ने कोशिश ही नहीं की. सीएसआईआर समाधान तो खोजती रही पर समस्याओं से उनका रिश्ता नहीं के बराबर रहा."

इस स्थिति का थोड़ा बहुत दोष उद्योगों के मत्थे भी है. देसी तकनीक के अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाले भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के प्रबंध निदेशक एन.के. शर्मा कहते हैं, "उद्योगों के लोग केवल प्रामाणिक तकनीक ही चाहते हैं. भारतीय प्रयोगशालाओं पर उनका कतई भरोसा नहीं. वे कोई खतरा उठाना नहीं चाहते और विदेशी अनुबंध ही पसंद करते हैं."

यह बहुत हद तक सही भी है. जब सरकार ने देसी तकनीक इस्तेमाल करने वालों को आयकर में छूट देने की घोषणा की तो अनुसंधान व विकास की करीब 100 इकाइयां तुरंत खुल गईं. लेकिन जब पाया गया कि इस छूट का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है तो यह छूट 1983 में वापस ले ली गई. हिंदुस्तान लीवर में अनुसंधान विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष के.के.जी. मेनन कहते हैं, "उद्योग का हर कदम बाजार पर निर्भर करता है. अनुसंधान करके कोई नया उत्पाद तैयार करने पर काफी लागत आती है जिसे उठाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं. अनुसंधान अमूमन नया उत्पाद तैयार करने के बजाए पुराने में सुधार के लिए ही किया जाता है क्योंकि लाभप्रद यही है."

बहरहाल, सबसे चिंता की बात देश के 15 विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विज्ञान छात्रों के स्तर को लेकर है. ये छात्र ही विज्ञान आंदोलन

एएसएलवी

एक अभिशप्त उड़ान

एक तरह से देखा जाए तो दमकते हुए रॉकेट की उड़ान ने भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजना की स्थिति स्पष्ट कर दी— तेजी से ऊपर चढ़ो, फिर गहरे समुद्र में गिरकर डूब जाओ. पिछले महीने जब देश में ही बना ऑगमेंटेड सेटेलाइट लांच वेहिकल (संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान) (एएसएलवी-डी 2) श्रीहरिकोटा से उड़ा और फिर 54 सेकंड बाद ही बंगाल की खाड़ी में गिर गया तो 25 साल में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक कड़ी टीका-टिप्पणियों की जद में आ गए.

लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकों के घावों पर कुछ मरहम भी लगा. इस हादसे के एक हफ्ते बाद भारत के त्रिआयामी उपग्रह "इन्सेट-1सी" (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) को दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना स्थित कॉरो अंतरिक्ष केंद्र से एरियन-3 रॉकेट सफलतापूर्वक परिक्रमा कक्षा में ले गया. इन्सेट-1 सी की संकल्पना भारतीय इंजीनियरों ने की, निर्माण फोर्ड एअरोस्पेस ने किया और उसे अंतरिक्ष की परिक्रमा कक्षा में पहुंचाया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने.

लेकिन देश में वैज्ञानिकों पर उदासी के जो बादल छाए थे, वह इस सफलता से भी नहीं छंटे. पहले एएसएलवी की असफलता के 15 महीने बाद एएसएलवी-डी2 का प्रक्षेपण तिरुअनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और आंध्र प्रदेश के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित श्रीहरिकोटा के 133 इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए बेहद चुनौती भरा काम था. पिछली 24 मई को छोड़ा गया पहला एएसएलवी विफल रहा था.

लेकिन 13 जुलाई को सारी मेहनत बेकार हो गई. राडारों और दूरीमिति (टेलीमिट्री) आंकड़ा संग्रह केंद्रों ने एएसएलवी के राते का जो ब्यौरा इकट्ठा किया उसके फौरी विश्लेषण से पता चलता कि रॉकेट के स्ट्रेप ऑन बूस्टर (विद्युत शक्तिवर्धन करने वाले उड़ान के बाद निर्धारित 52 सेकंड में अलग नहीं हुए और रॉकेट नीचे आ गिरा. लेकिन एएसएलवी पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक 220 सेकंड तक इससे संकेत हासिल करते रहे. अब वे उड़ान की विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए इनका विश्लेषण कर रहे हैं. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डा.एस.पी. गुप्ता कहते हैं, "हम अंदाज से कुछ नहीं कहना चाहते. हम अगले अगस्त तक पूरा विश्लेषण आने का इंतजार करेंगे." लेकिन एएसएलवी परियोजना के वैज्ञानिकों के बीच एक चर्चा यह है कि स्ट्रेप ऑन

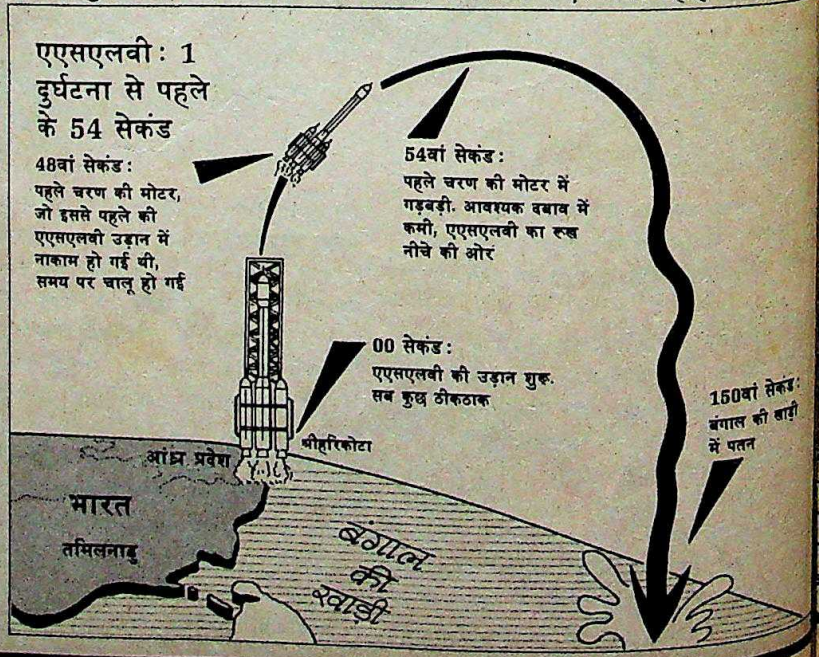

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्णधार हैं. लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक डॉ. एस.के. जोशी कहते हैं, "पूरी विश्वविद्यालय प्रणाली जर्जर हो गई है. प्रतिभाशाली विद्यार्थी अब विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आ रहे. ज्यादातर विभाग शोध में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, जबकि उन्हें तो शोध का केंद्र होना चाहिए."

अब सवाल यह है कि भारतीय विज्ञान को फिर से पटरी पर लाने का कोई उपाय है भी? विसंगति यह है कि इसे पटरी पर लाने का मुख्य जिम्मा सीएसआईआर संभाले हुए हैं. समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद इसने मूल ढांचे में कुछ बदलाव किए हैं. प्रयोगशालाओं से कहा गया है कि बस यों ही कोई अनुसंधान योजना शुरू करने के बजाय वे एक समय में कोई तीन क्षेत्र चुनकर उसी में अनुसंधान पर जोर दें. इन क्षेत्रों का चयन उन लोगों की सलाह से किया जाए जो अनुसंधान के नतीजों का इस्तेमाल करेंगे. ऐसे लोगों को अनुसंधान/सलाहकार समिति में शामिल किया गया है.

सबसे खास बात यह है कि प्रयोगशालाओं को अपने अनुसंधान के नतीजों को बेचकर अपने खर्च का एक तिहाई हिस्सा निकालना होगा. कई निदेशकों की नाराजगी के बावजूद सुधारों की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीद है सीएसआईआर में होने वाले फेरबदल से कई प्रयोगशालाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे भी अपने यहां सुधार करेंगी. एक वैज्ञानिक आधार तैयार करने के लिए मूलभूत अनुसंधान की तो बेहद जरूरत है ही, राष्ट्रीय विकास से सीधे जुड़ी तकनीक विकसित करने की भी सख्त जरूरत है. पानी, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण आदि की समस्याओं के समाधान के लिए सामान्य तकनीक की जरूरत है.

भारतीय वैज्ञानिकों में प्रतिभा की कमी नहीं है. और उन्होंने अक्सर यह दिखाया है कि लक्ष्य सामने हो तो वे पीछे नहीं हटते. अब वक्त आ गया है कि वे ऐसा ही कुछ कर दिखाएं.

■ "पूरी विश्वविद्यालय प्रणाली जर्जर हो गई है. प्रतिभाशाली छात्र अब विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आ रहे. ज्यादातर विभाग शोध में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, जबकि उन्हें तो शोध का केंद्र होना चाहिए"

डॉ. एस.के. जोशी
निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

अलग करने का जो निर्देश रॉकेट के कंप्यूटरों में भरा गया था वह प्रक्षेपक तक पहुंचा ही नहीं होगा. इस वजह से रॉकेट पर स्ट्रेप ऑन ईंधन के आवरण के जरिये कर्षण पैदा हो गया होगा और भारी दबाव के कारण वह टूट गया होगा. पिछले साल की विफलता की पड़ताल से जानकारी मिली थी कि स्ट्रेप ऑन तो अलग हो गए लेकिन पहले चरण की मुख्य मोटर प्रज्जवलित नहीं हो पाई थी.

एएसएलवी -डी2 का निर्माण एएसएलवी-डी 1 के लिए तैयार उपप्रणालियों से ही किया गया. इन दोनों रॉकेटों में दो विशेष व्यवस्थाएं थीं जो पहले वाले एएसएलवी-3 रॉकेटों में नहीं थीं. ये व्यवस्थाएं थीं :

- स्ट्रेप ऑन बूस्टर सिस्टम. इसमें मुख्य यान पर दो बूस्टर लगाए गए ताकि रॉकेट उड़ने के लिए जोरदार झटका लग सके.
- 'क्लोज्ड लूप गाइडेंस सिस्टम' (सीएलजीएस). यह एक तरह से रॉकेट का मस्तिष्क होता है. उच्च तकनीक से बनी यह प्रणाली रॉकेट को सही दिशा और सही गति में रखती है. यदि दिशा गड़बड़ाए तो यह उसे सही रास्ते पर भी लाती है.

साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के इंजीनियरों का कहना है कि दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है रॉकेट का वायुगतिक (एअरोडायनामिक) ढांचा. स्ट्रेप ऑन मोटर्स मुख्य यान पर दोनों तरफ से जुड़े रहते हैं. उड़ान भरने के बाद ये मोटर 49 सेकंड तक एक साथ जलते हैं और वाहक यान को सबसे महत्वपूर्ण पारध्वनिक क्षेत्र और अत्यधिक दबाव वाली स्थितियों से ऊपर ले जाते हैं. इन मोटरों के निर्धारित काम में रंच मात्र भी अंतर (यहां तक कि 3 प्रतिशत से भी कम) आने से उड़ान में व्यवधान आ सकता है.

इस बीच कई समितियां इस हादसे की जांच में जुट गई हैं. इनमें विशेषज्ञ समीक्षा समिति, विफलता विश्लेषक दल और प्रधानमंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति है. ये समितियां एएसएलवी के वायुगतिक ढांचे, प्रक्षेपण-क्षमता और नियंत्रण व्यवस्था की बारीकी से जांच-परख करेंगी और उसके बाद अंतरिक्ष प्रक्षेपण व्यवस्था के विकास की योजना बनाएंगी.

■ कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि स्ट्रेप ऑन मोटर्स अलग करने के लिए कंप्यूटर में भरा निर्देश प्रक्षेपक तक पहुंचा ही नहीं होगा. इस वजह से रॉकेट समुद्र में जा गिरा

विशेषज्ञ समीक्षा समिति की नियुक्ति और इसकी सिफारिशों का नतीजा यह भी हो सकता है कि एएसएलवी की दो और उड़ानों की योजना बदल जाए. स्ट्रेप ऑन मोटर्स और सीएलजीएस दोनों ही पोलर सेटेलाइट लांच वेहिकल (पीएसएलवी) में लगने वाली महत्वपूर्ण तकनीक है. पीएसएलवी रॉकेट तकनीक में व्यापक सुधार का परिणाम होगा. यह संवर्धित रॉकेट दो टन वजन के दूरसंवेदी उपग्रह को 90 किमी दूर ध्रुवीय कक्षा में ले जाने में समर्थ होगा जबकि एएसएलवी सिर्फ 150 किलो वजन के उपग्रह को इससे कहीं कम दूरी की कक्षा में ले जा सकता है.

हालांकि भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन (आईएसआरओ- इसरो) के अध्यक्ष प्रो. यू.आर. राव का कहना है कि पीएसएलवी विकास कार्यक्रम एएसएलवी परियोजना से अलग है. लेकिन दूसरे अंतरिक्ष इंजीनियरों को लगता है कि जब तक स्ट्रेप ऑन मोटर्स और सीएलएसजी व्यवस्था कसौटी पर खरी नहीं उतरती तब तक पीएसएलवी का प्रक्षेपण कार्यक्रम भी 1992 तक के लिए टल सकता है.

पीएसएलवी के अलावा 'इसरो' की और भी योजनाएं हैं. इन्सेट की ही श्रेणी के उपग्रह को कक्षा में भेजने के लिए जिओस्टेशनरी सेटेलाइट लांच वेहिकल (पृथ्वी की गति से परिक्रमा करने वाला संचार भू-उपग्रह प्रक्षेपण यान, जीएसएलवी) बनाने का प्रस्ताव अभी कागज पर ही है. उस पर अमल दूर की बात है.

दूरसंवेदी उपग्रह को कम दूरी की कक्षा में भेजने के लिए प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम तब तक शायद ही कोई उपलब्धि हासिल कर पाए. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को एएसएलवी की दोहरी विफलता से पैदा हुई निराशा से निबटना होगा और अपने रॉकेट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा. अच्छी बात यह है कि पिछले महीने के हादसे के बावजूद अधिकांश वैज्ञानिक यह कर सकने में खुद को सक्षम पाते हैं. जैसा कि एक वैज्ञानिक ने कहा, "एएसएलवी में हम विफल हुए पर इससे हमें और बेहतर करने की ताकत ही मिली है."

—**अमरनाथ के. मेनन**, श्रीहरिकोटा और बंगलूर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नेहरू के पत्र

भावनाएं, फूल और राजनीति

लेडी माउंटबेटन को लिखकर जी हल्का किया करते थे जवाहर

पंडित नेहरू को एडविना माउंटबेटन से बहुत कुछ कहना था. सो उन्होंने उन्हें ढेरों चिट्ठियां लिखीं. भारत के पहले प्रधानमंत्री की लिखी ये चिट्ठियां साउथ हैम्पटन के पास ब्रॉडलैंड्स में माउंटबेटन के पैतृक घर में टिन के एक संदूक में भरी पड़ी हैं. कुल 60 पौंड वजन की इन चिट्ठियों में जहां नेहरू का काव्यात्मक प्रवाह झलकता है, वहीं कुछ चिट्ठियों में हल्की-फुल्की बातें हैं और कुछ में गंभीर राजनैतिक मुद्दे भी.

नेहरू ने 1948 में माउंटबेटन परिवार के भारत छोड़ने के बाद से एडविना को चिट्ठियां लिखनी शुरू कीं. यह सिलसिला 1961 में एडविना की मौत तक जारी रहा. नेहरू ने एडविना से राज्य और राजनीति के मामलों की जिस विस्तार से चर्चा की है, इन चिट्ठियों का महत्व उसी में है. लगता है जैसे कोई डायरी लिखी गई हो. इनमें नेहरू इस कदर जोर देकर अपनी बात कहते हैं तथा अपने संदेह, उम्मीदें और गंभीर विचार व्यक्त करते हैं गोया 'उनके सामने एक अच्छा श्रोता बैठा हो.' ऐसा एडविना की अधिकृत जीवनी पर काम कर रहीं इतिहासकार और जीवनी लेखक जॉनेट मोर्गन का कहना है. लेडी माउंटबेटन की यह जीवनी कोलिंस अगले साल प्रकाशित कर रहा है.

माउंटबेटन परिवार के विशाल जॉर्जकालीन घर में चिट्ठियों का यह संदूक अभी हाल तक कहीं पड़ा हुआ था. अगस्त 1979 में अर्ल ऑफ बर्मा की हत्या के बाद ही इनका रहस्य भी खुला. तब ये चिट्ठियां लार्ड माउंटबेटन की अधिकृत जीवनी लिखने वाले फिलिप जीगलर के हाथ लगीं. लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं आया. यहां तक कि रिचर्ड हॉग द्वारा लिखित एडविना माउंटबेटन की 'अनधिकृत' जीवनी में भी इनका कोई हवाला नहीं है, न ही अटकलबाजियों से भरी ब्रिटीवी सिरीज 'द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया' में ही इनका कोई जिक्र है. हालांकि इसमें पंडित नेहरू और लेडी माउंटबेटन एक दूसरे को अपलक निहारते और गुलाब का आदान-प्रदान करते दिखाए गए हैं.

अब यह संदूक मोर्गन के लिए खोल दिया गया है. पर वे इनमें रखी चिट्ठियों के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं. उन्होंने 'इंडिया टुडे' को इतना ही बताया कि "तीन हफ्ते तक इन चिट्ठियों को लगातार पढ़ती रही." जब उनसे सभी भारतीयों के होंठों पर रहने वाला लाख टके का सवाल पूछा गया कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के संबंध किस तरह के थे? उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि चिट्ठियों के मुताबिक उनके संबंध भाव प्रवण और 'बहुत नजदीकी' थे. "ऐसे नजदीकी संबंध.... जिनमें दैहिक रिश्ते न तो जरूरी थे और न ही पर्याप्त. मैंने इसी तरह के रिश्ते वाली

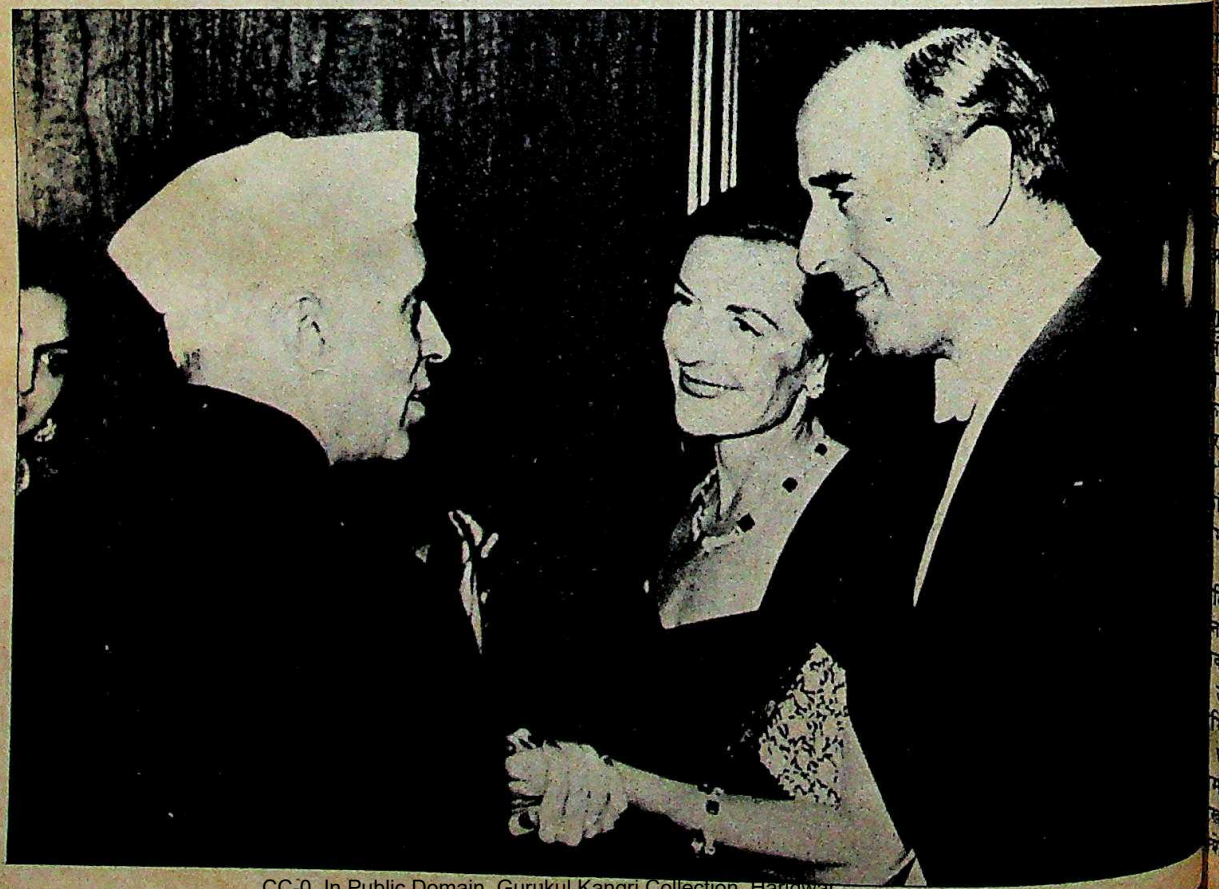

भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित एक भोज में नेहरू, एडविना और लॉर्ड मांउटबेटन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संन्यासिनी और उसके गुरु की चिट्ठियां भी मूढ़ी हैं."

इस बीच, लंदन में पत्रकारों और प्रकाशन हलकों में चिट्ठियों के इस खजाने की जोरदार चर्चा शुरू हो गई है. लेकिन उनकी जिज्ञासा चिट्ठियों के राजनैतिक मजमून को लेकर है, न कि रूमानी. उम्दा पतले कागज की कुछ चिट्ठियों में सहेजकर रखे गए कुछ कश्मीरी फूल भी हैं. अधिकतर हाथ से लिखी ये चिट्ठियां दो-दो, तीन-तीन पन्नों की हैं. टाइप की हुई चिट्ठियां छोटी हैं और उनमें सतही बातें ही हैं.

ज्यादा मजेदार तो कृष्ण मेनन के बारे में लिखी चिट्ठियां हैं. इनसे यह संकेत मिलता है कि नेहरू किस तरह लेडी माउंटबेटन को लिखकर अपना जी हल्का किया करते थे. चिट्ठियों में उन्होंने मेनन को रास्ते पर लाने में अपनी उलझन का जिक्र किया है. उस समय मेनन सेंट जेम्स के दरबार में उच्चायुक्त थे और काफी विवादास्पद भी. नेहरू उन्हें वापस दिल्ली बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि इससे उनके अच्छे दोस्त के अहं को किसी न किसी रूप में ठेस पहुंचेगी. जाहिर है, हजारों किलोमीटर दूर लेडी माउंटबेटन सरीखे किसी व्यक्तित्व से ही वे मेनन के स्वास्थ्य और मानसिकता के बारे में अपनी आशंकाएं जता सकते थे. लेकिन नेहरू मेनन को यह एहसास भी नहीं कराना चाहते थे कि वे उन्हें पसंद नहीं करते.

ज्यादातर चिट्ठियों में नेहरू ने राष्ट्रमंडल, अमेरिका और चीन की तरफ भारत के रवैये जैसे मुद्दों और भारतीय राजाओं से अपने रिश्तों पर बिना लाग-लपेट के लिखा है. ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी कुछ चिट्ठियों में नेहरू ने नए संविधान में क्या दर्ज हो और क्या नहीं, इन बातों की चर्चा भी की है. ऐसा अधिकृत सूत्रों का कहना है. इनमें कश्मीर के मुद्दे का भी राजनैतिक और भावनात्मक दोनों लिहाज से विस्तृत जिक्र है. इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उसकी समस्याओं पर भी गंभीरता से अपने विचार रखे हैं.

लेडी माउंटबेटन भारतीय राजनीति की जटिलताओं और परिवर्तनशीलता से भले ही अभिज्ञ रही हों पर सामाजिक आचार-व्यवहार का ज्ञान तो उन्हें था ही. ऐसा लगता है उन्होंने नेहरू को सलाह दी होगी कि विभिन्न नेताओं से वे कैसे निबटें. एक जज्बाती चिट्ठी में तो नेहरू का अपने ही दल के प्रति संदेह भी झलकता है. उन्होंने लिखा है कि वे बर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू के नक्शेकदम पर चलकर संन्यासी बनना चाहते हैं ताकि वे जीवन में बड़ी चीजों के बारे में सोच सकें. जाहिर है इस समय उनके कंधों पर सरकारी काम बढ़ गया था.

चिट्ठियों में पद्मजा नायडू और 'पीली वस्त्रधारी एक रहस्यमय औरत' का भी बार-बार हवाला आया है. राजकुमारी अमृत कौर का भी प्रायः जिक्र हुआ है. कई बार लगता है कि 'जवाहर' और 'एडविना' (दोनों एक दूसरे को इसी नाम से संबोधित करते थे) एक विशाल सामाजिक क्षेत्र के बारे में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं. पर लेडी माउंटबेटन ने नेहरू की चिट्ठियों का क्या जवाब दिया, यह उसी वक्त मालूम हो सकेगा जब नेहरू के नाम उनकी लिखी चिट्ठियां प्रकाशित होंगी. फिलहाल ये चिट्ठियां गांधी परिवार के पास हैं. लेडी माउंटबेटन के नाम नेहरू की लिखी चिट्ठियां ब्रेबोर्न ट्रस्ट की संपत्ति हैं. लॉर्ड ब्रेबोर्न की शादी माउंटबेटन दंपती की बड़ी बेटी पैट्रीशिया से हुई है.

नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच कैसे रिश्ते थे और माउंटबेटन परिवार में नेहरू की क्या जगह थी, इस बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए मोर्गन की पुस्तक प्रकाशित होने तक इंतजार करना होगा. अगाथा क्रिस्टी की अधिकृत जीवनी लिखने वाली मोर्गन की पहुंच ब्रेबोर्न ट्रस्ट की विशाल पुरालेखीय सामग्री तक है. लेकिन ताज्जुब की बात है कि ब्रॉडलैंड्स में, जहां कई राष्ट्र प्रमुखों और सम्राटों के दस्तखत वाले उनके चित्र लगे हैं, विजयलक्ष्मी पंडित की भी एक तस्वीर यहां है, नेहरू का कोई चित्र नहीं है. फिर भी चिट्ठियों में सहेजे गए कश्मीरी फूल और उनके सुंदर शब्द आसपास सुगंध बिखेरते हैं.

—मधु जैन

नेहरू ने एडविना से राज्य और राजनीति के मामलों की जिस विस्तार से चर्चा की है, इन चिट्ठियों का महत्व उसी में है. लगता है जैसे कोई डायरी लिखी गई हो. नेहरू संदेह, उम्मीदें और गंभीर विचार इस तरह व्यक्त करते हैं गोया उनके सामने अच्छा श्रोता बैठा हो

ब्रॉडलैंड्स में माउंटबेटन का पैतृक घर

नेहरू और मेनन: भावनात्मक लगाव

मेनन को रास्ते पर लाने की अपनी उलझन का भी जिक्र नेहरू ने इन चिट्ठियों में किया है. मेनन की विवादास्पद छवि के कारण वे उन्हें लंदन से वापस दिल्ली बुलाना चाहते थे लेकिन डरते भी थे कि इससे उनके अच्छे दोस्त के अहं को ठेस पहुंच सकती है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

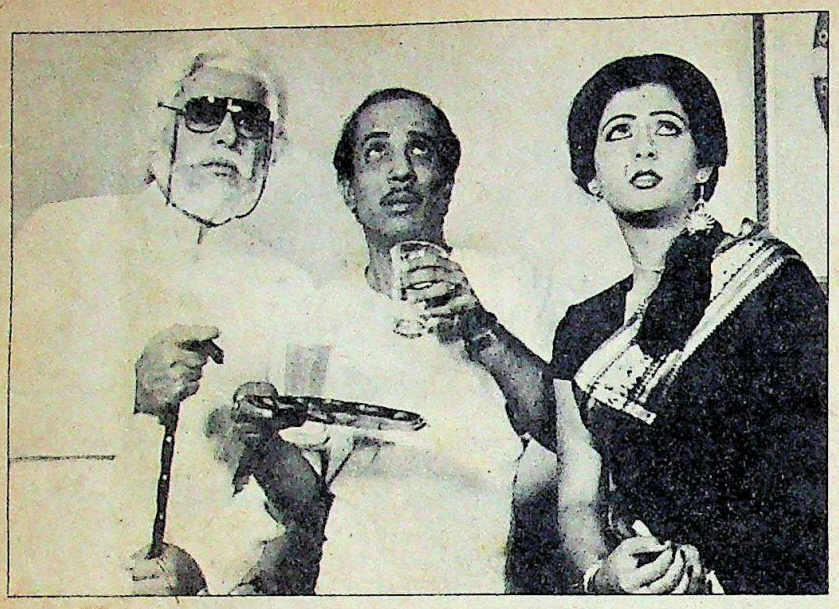

'पीछा करो'

लचर फंतासी, फूहड़ हास्य

मगर निर्देशन, संपादन, अभिनय की कुछ चमक भी

कलाकारों के अपने कुछ कलागत आग्रह होते हैं जो उनकी पहचान बनाते हैं. सिनेमा के परदे पर अभिनेता-अभिनेत्रियों के लिए ये आग्रह उनके मैनरिज्म में बदल जाते हैं. लेकिन परदे के पीछे से अभिनेता-अभिनेत्रियों को कठपुतली की तरह नचाने वाले निर्देशक के आग्रहों को क्या कहा जाए? शायद इसके लिए कोई सटीक शब्द नहीं है. मगर क्योंकि फिल्म का दारोमदार सबसे ज्यादा निर्देशक पर होता है, इसलिए उसके आग्रह फिल्म के लिए महत्वपूर्ण हो उठते हैं. यह अलग बात है कि बॉक्स आफिस पर फिल्म के नतीजों को वे उतना प्रभावित नहीं करते.

चाहे सीरियल 'करमचंद' हो या फिल्म 'जलवा,' दोनों में ही निर्देशक पंकज पाराशर के अपने आग्रह— अपराध, सस्पेंस, कामेडी, रफ्तार, आड़े-तिरछे कैमरा मूवमेंट और तेज व तीखा विदेशी संगीत तथा नृत्य—मुखर थे. ये ही आग्रह पिछले पखवाड़े रिलीज हुई 'पीछा करो' में भी मौजूद हैं. लेकिन जहां करमचंद और 'जलवा' में अभिनय और कहानी के बेहतर ताने-बाने की जमीन थी, वहीं 'पीछा करो' में यह आधार नदारद है. कहानी के नाम पर यहां एक अपराध फंतासी है और कामेडी के नाम पर (कुछ दृश्यों को छोड़ दें तो) जैसे बच्चों को हंसाने की कोशिश है.

निर्माता मुहम्मद इब्राहीम खां, राज कुमार जैन और सुरेंद्र सिंह की 'पीछा करो' करीब पांच साल पहले बननी शुरू हुई थी और डेढ़ साल पहले बन भी चुकी थी. निर्देशक पंकज पाराशर के नाम पर किसी तरह यह फिल्म सिनेमा हॉल का मुंह देख सकी. फिल्म के रिलीज होने का इंतजार सबसे ज्यादा बेताबी से नायिका रोमा माणिक को करना पड़ा है. रोमा की नगण्य-सी भूमिकाओं वाली फिल्में और भी आई हैं लेकिन नायिका के रूप में उनका कैरियर 'पीछा करो' पर ही टिका था. इसके रिलीज न हो पाने से पांच साल से बंबई में हाथ-पैर मार रही रोमा को कोई और बड़ी भूमिका नहीं मिल सकी. अभी केवल 'महाभारत' सीरियल में माद्री का पात्र साकार करने का काम ही उनके पास है. बहरहाल, रोमा आज की कई दूसरी हीरोइनों से खूबसूरती, फिगर और अभिनय में ज्यादा सक्षम दिखाई दीं. फारूक शेख गीतों की उछल-कूद में भोंडे नजर आते हैं, हालांकि फिल्म में सबसे अच्छा अभिनय उन्हीं का है.

थोपे गए हालात में रवि वासवानी, सतीश शाह और अनुपम खेर की प्रतिभा का

(बाएं से) फारूक, राजेश और रोमा: हंसाने की कोशिश

इस्तेमाल नहीं हो सका जो किसी अच्छी कहानी में हो सकता था जहां अभिनय के लिए मौके भी ज्यादा होते. इनके बजाय राजेश पुरी और विजू खोटे कम दृश्य मिलने के बावजूद असर छोड़ते हैं. अमजद खां तब इतने मोटे नहीं थे जब यह फिल्म शुरू हुई थी, मगर सुधीर के साथ उनका बार-बार कुत्ते-बिल्ली की आवाजें निकालना खटकता है.

अमजद खां एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर बने हैं जो देश की एक दुश्मन एजेंसी के सरगना तक पहुंचने के लिए उस गिरोह को अपने देश के झूठे खुफिया सुराग सप्लाई करता है. लेकिन कभी उनके हाथों नौकरी से हटाए गए दो व्यक्ति (रवि वासवानी और सतीश शाह) उन्हें सचमुच का अपराधी मानकर उनका पीछा करते हैं. सफल न होने पर वे ब्रिगेडियर की लड़की (रोमा) के पति (फारूक शेख) को ब्लैकमेल कर उसे ब्रिगेडियर का पीछा करने को मजबूर कर देते हैं. पूरी फिल्म में असामान्य हरकतों से हंसाने की कोशिश की गई है. रवि वासवानी और सतीश का ब्रिगेडियर के घर के बाहर लेटरबाक्स बनकर बैठना तो ठीक था. पर बाद में निर्देशक ने बार-बार उन्हें पेड़ बना कर जासूसी करवाई है. महमूद की 'पड़ोसन' में एक साथ कई लोगों का छिपने के लिए पेड़ उठाकर चलने वाला दृश्य इससे कहीं बेहतर था. अंत में ब्रिगेडियर का राज खुलता है और दुश्मन एजेंसी (सरगना अनुपम खेर सहित) धर ली जाती है. संगीत (आनंद मिलिंद) और फोटोग्राफी (अजय शर्मा व श्याम पल्लव) ने जरूर फिल्म का साथ दिया है. पर राजेश मजूमदार न अच्छी फंतासी दे पाए हैं और न एक अच्छा कामेडी के लायक संवाद.

ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म ही लचर हो. कई दृश्यों में निर्देशन और संपादन का जादू दर्शकों को गुदगुदाता है. लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितिजन्य सहज हास्य नहीं है, जो किसी भी सफल कामेडी फिल्म की अनिवार्य शर्त है. बल्कि यहां हास्य के लिए नाटकीय परिस्थितियां गढ़ी गई हैं. फंतासी का आधार की सचाइयों से तालमेल न होने के कारण यह सब खोखला लगता है.

इस देश में यों भी कामेडी फिल्में बहुत कम बनी हैं. लेकिन जो भी स्तरीय कामेडी फिल्में रहीं उनमें 'पीछा करो' को कोई ऊंचा दर्जा नहीं दिया जा सकता.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

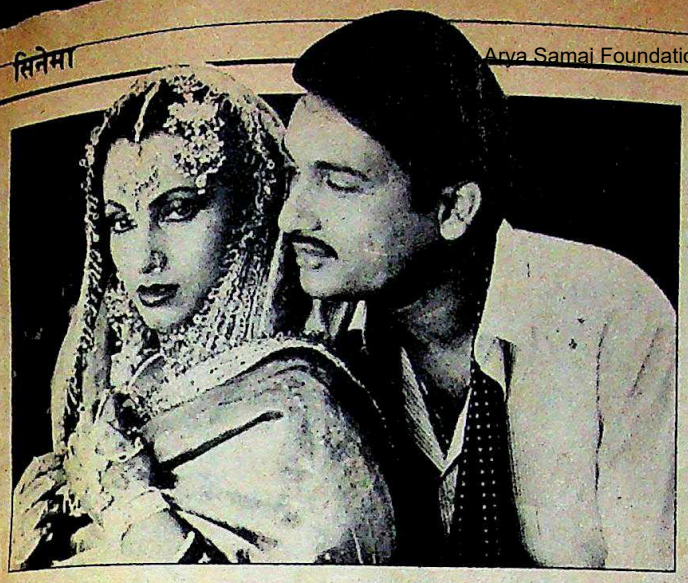

पति परमेश्वर

विवादों की उलझन

स्त्री स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार का मामला

शेखर सुमन के साथ डिंपल; और (बाएं) सुधा चंद्रन

नारी स्वतंत्रता के हामी, नैतिकतावादी, उदारवादी, प्रगतिशील सभी एक हिंदी फिल्म को लेकर आपस में जूझ रहे हैं. हालांकि सामान्य तौर पर यह फिल्म कोई विवाद पैदा नहीं करती. सभी पक्षों के घालमेल ने मामले को और पेचीदा बना दिया है. उदारवादियों और नैतिकतावादियों को अपना समान लक्ष्य नजर आ रहा है तो स्त्री स्वतंत्रता के हामी सेंसर बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं.

पिछले पखवाड़े यह विवाद उस वक्त और गहरा गया जब बंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम.सी. प्रताप ने निर्माता आर.के. नैय्यर की फिल्म 'पति परमेश्वर' पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (केफिप्रबो) द्वारा लगाई रोक हटा दी. न्यायमूर्ति प्रताप ने कुछ काट-छांटकर फिल्म को 'यू ए' (माता-पिता के साथ देखने लायक) प्रमाणपत्र के साथ प्रदर्शन की इजाजत दे दी. फिल्म के आलोचकों का कहना है कि इस फैसले से 18वीं शताब्दी के रूढ़िवादी विचारों को बल मिला है. यह महिलाओं की अधीनता स्वीकार करने की भावना को महिमामंडित करती है. इसलिए इसके प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए.

'पति परमेश्वर' एक ऐसी समर्पित पत्नी रेखा (सुधा चंद्रन) के बारे में है जिसका पति (शेखर सुमन) अपना ज्यादातर वक्त अपनी प्रेमिका (डिंपल) के साथ गुजारता है. पति का साथ छोड़ने के बजाय रेखा पति-पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने को तवज्जो देती है. जब पति को लकवा मार जाता है तो वह उपवास रखती है, उसकी सेवा करती है और उसे उसकी प्रेमिका के पास इस उम्मीद में ले जाती है कि वह फिर से सही सलामत हो जाएगा. अंततः पति अपनी हरकतों पर पछताता है और पत्नी के पास वापस आ जाता है. पत्नी उसे स्वीकार कर लेती है.

लेकिन फिल्म केफिप्रबो के नए नियम 2(4) (अ) का उल्लंघन करती है. इसके मुताबिक सेंसर ऐसी किसी भी फिल्म पर रोक लगा सकता है जिसमें ऐसे कोई दृश्य या डायलाग हों जिनमें स्त्री को पुरुष की दासी बताया गया हो या फिर ऐसी दासता को नारी की काबिलेतारीफ खूबी के रूप में उभारा गया हो. लेकिन सुधा चंद्रन फिल्म का पुरजोर बचाव करती हैं. नैय्यर दलील देते हैं, "मेरा मत है कि दांपत्य की रक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए और इसके लिए पत्नी को त्याग करना चाहिए. यह तो भारतीय परंपरा की ही परीक्षा है." लेकिन केफिप्रबो बंबई के क्षेत्रीय अधिकारी अण्णा दाणी इससे सहमत नहीं.

भारतीय चलचित्र अधिनियम (1952) के तहत सेंसरशिप के मामलों में आखिरी फैसला देने वाले पंचाट ने फैसला दिया, "भले ही इसके कितने भी हिस्सों को काट-छांट दिया जाए लेकिन फिल्म का आपत्तिजनक असर खत्म अथवा कम नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश है जो हमारे वर्तमान समाज की मान्यताओं से मेल नहीं खाते..." लेकिन न्यायमूर्ति प्रताप की राय है, "रेखा भारतीय नारी की आंतरिक दृढ़ता की एक मिसाल है."

केफिप्रबो ने अब फैसले के खिलाफ स्थगनादेश हासिल कर लिया है और प्रमाणपत्र जारी करने के न्यायमूर्ति प्रताप के अधिकार को चुनौती दी है. नैय्यर के वकील अतुल सीतलवाद का कहना है, "यह (सेंसर का नया नियम) पूरी तरह गैरकानूनी है. आजादी की असली कसौटी तो इसमें है कि आप अपने से एकदम असहमत व्यक्ति को कितनी आजादी देते हैं." इसलिए 'पति परमेश्वर' सेंसर के नए नियमों की वैधता की परीक्षा का मामला भी बन गई है क्योंकि केफिप्रबो के अधिकारी यदि जरूरी हुआ तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के मूड में हैं. फिल्म आलोचकों को फिल्म में ऐसी घातक बातें नजर आई हैं कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी समझौता करने को राजी दिखाई दे रहे हैं. दूसरी ओर फिल्म समर्थकों का कहना है कि चूंकि फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए इसे प्रदर्शन का पूरा हक है. बहरहाल, इस फिल्म से उठे विवाद की जद में अब भारतीयों का मनोरंजन करने वाले घटिया विचार भी आ गए हैं.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'सलाम बांबे!'

हाशिए पर खड़े लोगों की कथा

युवा निर्देशिका की पहली ही फिल्म को अंतरराष्ट्रीय सम्मान

शफीक (ऊपर) और उसका गिरोह

बंबई में ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर दो. एक छोर पर लोहे के दो खंभों पर टिके लकड़ी के तख्ते पर लेटा 12 साल का एक लड़का. उसके पीछे धूप में सूखती एकदम नई जीन और टी-शर्ट. ये शानदार कपड़े हैं शफीक सैयद के, जो महज फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ही नहीं, 'सलाम बांबे!' का नायक भी है. निर्देशिका की इस पहली ही फिल्म को पिछली मई में कान फिल्म महोत्सव में सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए 'कैमरा द ओर' पुरस्कार मिला.

न्यूयॉर्क में रह रहीं 'सलाम बांबे!' की 30 वर्षीया निर्देशिका मीरा नायर पुरस्कार के सिलसिले में अपने पात्रों के साथ जश्न मनाने बंबई आई हैं. फिल्म में भूमिका निभाने वाले 17 फुटपाथी बच्चों में से ज्यादातर अभी कहीं जमे नहीं हैं.

फिल्म फुटपाथ पर पले-बढ़े बच्चों के जानदार अभिनय के कारण उनके जीवन का आईना लगती है

लेकिन कैमरे के सामने अदाकारी के अप्रत्याशित अनुभव ने उन्हें बदल दिया है.

कुछ बच्चे अपने गांवों को लौट गए, कुछ स्कूल जाते हैं तो कुछ काम करने लगे जबकि कुछ फिर वहीं फुटपाथ पर लौट आए हैं. सिर्फ शफीक ही असमंजस में है.

(नीचे) हंसा अपने परिवार के साथ

सभी फोटो: सौनी तारापोरवाला

कान फिल्मोत्सव में हंसा को वाहवाही मिली. अब वह टीवी सीरियल में आ रही है

कर्नाटक के एक गांव से भागकर आने के बाद हुई अपनी पुरानी जिंदगी और पुरस्कृत फिल्म के नायक के रूप में अपनी नई जिंदगी के बीच झूल रहा है. उसने कालिक फिल्म अभिनेता बनने के सपने तो बुने पर इसके लिए वह कुछ नहीं चाहता. एक से वह नटखट बालक की तरह ही हकबकाया है, जिसकी भूमिका 'सलाम बांबे!' में निभाई है.

10 साल का कृष्ण सर्कस में काम करता है

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Harvard

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मीरा नायर

'असली परीक्षा तो भारत में'

कान फिल्म समारोह में अपनी पहली फीचर फिल्म पर पुरस्कार हासिल करने के बाद मीरा नायर की बंबई वापसी का एक और मतलब था— फुटपाथ के उन बच्चों से पुनर्मिलन, जिन्होंने उनकी इस कामयाबी में योगदान दिया. ब्यूरो प्रमुख ***एम. रहमान*** *ने उनकी फिल्म 'सलाम बांबे!' के विभिन्न पहलुओं पर उनसे बातचीत की. बातचीत के अंश:*

● ***'सलाम बांबे!' सरीखी असामान्य फिल्म बनाने का फैसला आपने कैसे किया?***

नामस भोजानी

फिल्म की प्रेरणा मुझे बंबई के फुटपाथों पर पलते-बढ़ते उत्साही बच्चों को देखकर मिली. सबसे पहली छवि जो मेरे मानस-पट पर अंकित हुई वह थी ट्रैफिक जाम के वक्त मेरी टैक्सी को घेरे बच्चों की— बुलबुले उड़ाते, कलाबाजियां खाते, गाना गाते बच्चे और पहिएदार पटरे पर बैठा एक अपंग बच्चा. ये बच्चे ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां मुकद्दर ने उन्हें सिवाय जिंदगी के और कुछ नहीं दिया. इसके बावजूद वे मस्ती से जीने के रास्ते ढूंढ़ लेते हैं. इस तथ्य ने मुझे आकर्षित किया.

सोनी तारपोरवाला के साथ जब मैंने कुछ महीने उनकी जिंदगी को नजदीक से देखा तो उनसे मेरा जुड़ाव और गहराया. पटकथा तैयार करते हुए मुझे लग गया था कि यदि हम कभी फिल्म बनाने बैठे तो हमें फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों से ही भूमिकाएं करवानी पड़ेंगी.

● ***जब आपने बच्चों से कहा कि आप उन पर फिल्म बनाने जा रही हैं तो क्या उन्होंने भरोसा कर लिया?***

हमने नाच, गाने और कामचलाऊ कसरतों से शुरुआत की. जैसे-जैसे उनकी झिझक टूटी उनकी दिलचस्पी जगी.

● ***क्या कभी लगा कि आप पर अपने फायदे के लिए फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के इस्तेमाल का आरोप भी लग सकता है?***

हम शुरू से ही इस बात के प्रति सचेत थे कि यह फिल्म उन्हें और हमें दोनों को बदलकर रख देगी और जो रिश्ता बन गया है उसकी वजह से हम पर जिम्मेदारी आएगी. हमने कभी कोई ऐसा वादा नहीं किया जिसे हम पूरा न कर सकते हों. हमने उन्हें काम के बदले मजूरी दी. मजूरी की कुछ रकम सावधि जमा खातों में जमा करवा दी फिल्म पूरी होने के बाद बाल मनोविज्ञानी दीनाज स्टेफोर्ड बच्चों में निरंतर काम करते रहे. हमने भी उनसे संपर्क रखा. अब हम दीनाज के तहत इन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र बनाने की सोच रहे हैं.

मेरी फिल्म लोगों को फुटपाथी बच्चों का दुख-दर्द बांटने की प्रेरणा देती है तो मुझे खुशी होगी"

● ***क्या आप 'सलाम बांबे!' से दुनिया को बदलने की उम्मीद रखती हैं?***

मैं कोई समाज सुधारक अथवा कोई साम्यवादी फिल्म निर्माता नहीं हूं. लेकिन मेरी फिल्म लोगों को फुटपाथ के बच्चों का दुख-दर्द बांटने की प्रेरणा देती है तो मुझे खुशी होगी.

● ***कान में कैसी प्रतिक्रिया हुई?***

लोग फिल्म देखकर सुबक रहे थे, चीख रहे थे. फिल्म खत्म होने के बाद लगातार 15 मिनट तक तालियां बजती रहीं. दरअसल फिल्म उनके दिलों को छू गई. मेरे लिए यही तोहफा था.

से निकाले जाने पर बंबई चला आता है. गांव में मां को देने के लिए वह 500 रु. कमाने के सपने देखता है. लेकिन शहर पहुंचते ही वह वहां की भागदौड़ में खो जाता है और पुलिसवालों, चकलों, यातायात, सनकी लोगों, दलालों, नशीली दवाओं तथा देह व्यापार, फिल्मों की असंभव कपोल-कथाओं आदि के दुश्चक्र से घिर जाता है.

कृष्ण सबसे पहले गली-मुहल्लों में चाय और पावरोटी बेचने का धंधा शुरू करता है. इस दौरान उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो आखिर उसकी जिंदगी बदल देते हैं. जैसे 25 वर्षीय चिल्लम आवारा दादा है जो वेश्यालयों के बेताज बादशाह. बाबा के लिए नशीली दवाएं बेचकर गुजारा करता है. हालात के मुताबिक ढल जाने वाली वेश्या रेखा जो बाबा के साथ रहती है; और रेखा की आठ साल की बच्ची मंजू.

तभी नेपाल की एक अक्खड़ युवती 'सोलासाल' भी इस दुनिया में प्रवेश करती है. उसे धंधा करवाने के लिए जबरदस्ती बंबई लाया गया है. कृष्ण बेखबरी में उन सबकी जिंदगी में उत्प्रेरक का काम करता है और आखिरकार पैसे के अलावा दोस्तों से भी हाथ धो बैठता है. अब वह उतना ही बेसहारा है जितना पहली बार शहर पहुंचने पर था.

शफीक की जिंदगी भी कृष्ण से कम जटिल नहीं रही है. बंगलूर के निकट एक गांव में मजदूर परिवार में पैदा हुए शफीक की चार बहनें और तीन भाई हैं. चार बरस पहले घर से भागने से पहले वह गांव में साइकिल की दुकान पर काम करता था. बंगलूर में दो साल आवारा भटकने के बाद अक्तूबर 1986 में वह बंबई आकर कबाड़ चुनने का काम करने लगा. चर्चगेट स्टेशन से सटी एक दरगाह के आसपास वह अपनी सहेली के साथ मंडराता रहता. पिछले साल जून में वह रंगमंच निर्देशक बेरी जॉन द्वारा मीरा नायर की फिल्म की तैयारी के सिलसिले में आयोजित कार्यशाला के लिए चुन लिया गया. वहां शफीक ने अभिनय में अपनी छाप छोड़ी. सितंबर में गणेश चतुर्थी के दिन जब शूटिंग शुरू हुई तो उसे फिल्म का मुख्य पात्र बना दिया गया.

लेकिन शफीक के लिए कल्पना और वास्तविकता में अभी भी गहरा रिश्ता है. मीरा नायर कहती हैं कि कार्यशाला का मकसद फुटपाथी बच्चों को अभिनय सिखाना ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी योग्यता और महत्व का अहसास कराना भी था, उनमें यह भावना पैदा करना था कि वे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके जिंदगी में क्या कुछ कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकते हैं. बहुत से बच्चों ने तो अतीत से नाता तोड़ लिया है. अल्फर्ड एंथनी और चंद्रशेखर नायडू अब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में चपरासी बन गए हैं. निगम ने दूरदर्शन, ब्रिटेन के चैनल फोर टीवी, फ्रांस के काडरेज और नायर की मीराबाई फिल्म्स के साथ मिलकर ही 'सलाम बांबे!' का सहनिर्माण किया था. चंद्रशेखर ने तो निगम की एक दूसरी फिल्म में सिनेमा टिकट के ब्लैकिए की भूमिका निभाई है. शफीक को भी निगम की छत्रछाया मिली पर वह उससे अलग हो गया.

कुछ बच्चों ने तो 'सलाम बांबे!' के जरिये अपने अरसे से संजोए सपनों को साकार किया है. 17 साल का चंद्रशेखर काफी समय से बिछुड़ी अपनी मां और बहन

मिक इपस्टीन

नाना पाटेकर के साथ फुटपाथी बच्चे

को बंबई की सैर कराने के लिए नागपुर से लिवा लाया. 15 साल का रशीद पढ़ने और बेरी जॉन की रंगमंच कार्यशाला में काम करने के लिए दिल्ली चला गया है. 12 साल के सर्फुद्दीन ने अपनी कमाई बिहार के एक गांव में अपने परिवार को उनके मकान का कानूनी कब्जा दिलाने में खर्च की. अब वह दिल्ली में रशीद के साथ रह रहा है. 15 साल के मनोज के लिए तो उसकी जिंदगी में आए बदलाव और भी दिल को छू लेने वाले रहे हैं. इन दिनों वह नेत्रहीन बच्चों को देवताओं की मूर्तियां बनाना सिखाने का काम करता है.

बहुत से बच्चे बड़े होने पर फिल्म स्टार बनने की आकांक्षा रखते हैं. फिल्म की दूसरी बाल अभिनेत्री, आठ साल की हंसा को सिद्धार्थ काक के अगले टीवी सीरियल में एक भूमिका मिल भी चुकी है. नायर के मुताबिक अतिसुंदर हंसा को कान फिल्मोत्सव में खूब वाहवाही मिली. वहां की दुनिया बंबई जिमखाने के सामने फुटपाथ वाले उसके घर से बिलकुल अलग ही थी. हंसा का बाप सड़क मरम्मत करने वाले दल में काम करता है और मां लक्ष्मी पुराने कपड़ों के बदले स्टील के बर्तन बेचती है. उसके चार भाई-बहन हैं. वे कई साल से क्रॉस मैदान क्रिकेट ग्राउंड की लोहे की चारदिवारी से प्लास्टिक शीट बांधकर बने घर में रहते आ रहे हैं. पर अब वहां भी खतरा घिर आया है. महानगरपालिका ने उसके परिवार समेत अवैध मकान बनाकर रह रहे सभी लोगों को बेदखली का नोटिस दे दिया है. अधिकारी उन्हें कोई दूसरी जगह भी नहीं दे रहे. हंसा की कमाई से उसकी मां ने फुटपाथ पर एक भोजनालय खोल लिया है. हंसा और उसकी बहन रामीला अब स्कूल जाने लगी हैं.

भुवनेश्वर में जन्मीं नायर ने दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया और फिर हॉवर्ड से 'विजुअल स्टडीज' की डिग्री हासिल की. अपने सहपाठी और फोटोग्राफर मिक इपस्टीन से शादी कर लेने पर वे न्यूयॉर्क के बोवेरी इलाके में बस गईं. 'जामा मस्जिद स्ट्रीट जर्नल' और 'सो फार फ्रॉम इंडिया' नामक दो वृत्तचित्र बनाने के बाद जब उन्होंने विवादास्पद 'इंडिया कैबरे' बनाई तो चर्चित हो गईं. यह वृत्तचित्र बंबई की दो कैबरे नर्तकियों की कहानी पर है. इसे जनवरी 1986 में हैदराबाद फिल्मोत्सव में दिखाया गया, जिसके बाद गर्भ परीक्षण के बारे में एक फिल्म दिखाई गई.

'सलाम बांबे!' शहरी जिंदगी के कगार पर खड़े लोगों के नाटकीय जीवन को दर्शाती है. फुटपाथी बालकों के अलावा फिल्म में रघुवीर यादव ने चिल्लम, नाना पाटेकर ने बाबा, अनीता कंवर ने रेखा और शौकत आजमी ने कमाठीपुरा की गली नंबर 14 के वेश्यालय की बाई की भूमिका बखूबी निभाई है. कान में यूरोप के प्रमुख फिल्म महोत्सव में इस फिल्म को मिला सम्मान निश्चय ही भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर है.

अनेक देशों में इसे प्रदर्शित करने की तैयारियां हैं. अकेले पेरिस में ही अगस्त में यह 11 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी. 'कैमरा द ओर' पुरस्कार के साथ ही इसे 40,000 डॉलर (53 लाख रु.) का चेक भी मिला है जिसे पुरस्कार विजेता निर्देशिका अमली फिल्म की तैयारियों पर खर्च करेंगी. नायर अब एक ऐसे आप्रवासी भारतीय परिवार (पति, पत्नी और बेटी) पर भी फिल्म बनाने की सोच रही हैं जो उगांडा की अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर अमेरिका में मोटल खोल लेता है.

बहरहाल, भारत में उनकी फिल्म 'सलाम बांबे!' अक्तूबर में दिखाई जाएगी. इसके विशेष शो आयोजित किए जाएंगे जिनमें फुटपाथी बालकों के बनिस्बत एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए पैसा जुटाया जाएगा.

—एम. रहमान

फिल्म में काम कर चुके कुछ बच्चे गांव लौट गए हैं तो कुछ स्कूल जाने लगे हैं और कुछ बच्चे धंधे में लग गए हैं लेकिन कई फुटपाथों पर ही हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेटर्स टू ए डॉटर

संवेदनाओं का साझापन

इंदिरा को लिखे नेहरू के पत्रों का भावुकता भरा मंचन

इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, "यदि मुझे अपने पिता के बारे में बताना हो तो मैं कहूंगी वे मानवता की प्रतिमूर्ति थे. दरअसल, वे बहुत ही संवेदनशील थे. मैं तो कहूंगी कि वे नेता से कहीं ज्यादा कवि थे."

दिवंगत श्रीमती गांधी के कान्वेंटी लहजे में कहे गए ये शब्द न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे के एक छोटे थिएटर के अंधेरे सभागार में गूंजते ही अमेरिकी नाटककार लवोन म्यूलर के एक नाटक 'लेटर्स टू ए डॉटर फ्रॉम प्रिजन: इंदिरा ऐंड नेहरू' पर से परदा उठ गया.

किशोरी इंदिरा को लिखे गए जवाहर लाल नेहरू के ये पत्र भारत में 'ग्लिंप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन पश्चिम में नेहरू को सिर्फ राजनीतिक के रूप में ही जाना जाता है. इसलिए जब म्यूलर ने इन चिट्ठियों को पढ़ा तो वे पिता-पुत्री के बेहद आधुनिक रिश्ते के बारे में जानकर अवाक रह गईं. खुद एक कद्दावर मां, शिक्षक और बुद्धिजीवी होने के नाते म्यूलर का नेहरू के व्यक्तित्व के उन पहलुओं से प्रभावित होना स्वाभाविक था. लिहाजा उन्होंने अपने नाटक में 'एक विशेष पिता और एक विशेष पुत्री के बीच के संबंधों के मानवोचित गुणों' के पुनर्सजन की ठान ली. हालांकि म्यूलर की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं कि किसी दूसरी संस्कृति की जड़ तक पहुंच सकें. फिर भी उन्होंने भारत की आत्मा को बड़े चमत्कारी ढंग से पकड़ा. म्यूलर इसका श्रेय भारतीय निर्देशक विजया मेहता को देती हैं जिन्होंने पटकथा तैयार की. म्यूलर और मेहता को न्यूयॉर्क में एक साथ लाने का श्रेय 'द वुमंस प्रोजेक्ट' को है.

यह मुनाफा न कमाने वाला नाट्य समूह है जो महिला कलाकारों को बढ़ावा देता है.

मेहता ने चमकीली आंखों वाली किरण वैराले (इप्टा में सक्रिय) को इंदिरा की और रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 'गांधी' में नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाने वाले ब्रॉडवे के कलाकार हर्ष नैयर को नेहरू की भूमिका दी. नाटक को भारतीय रूप देने के लिए म्यूलर के साथ हुए समझौते के मुताबिक मेहता ने नाटक की मूल पटकथा में फेरबदल किए और कुछ अतिरिक्त पात्र जोड़ दिए. मसलन खामोश रहने वाली कमला नेहरू और मुखर स्वरूप रानी.

नैयर और वैराले: बुद्धि व प्यार का द्वंद्व

जब मेहता ने इसमें स्थानीय रंग भरा तो वे यह सवाल करने से नहीं चूकीं कि "क्या अमेरिकियों के लिए इसका कोई मतलब है?" इस तरह नाटक की पटकथा में बरगद के पेड़, लू, मानसून और मिठाइयों की जगह बन गई. लेकिन मेहता के इस विचार को नहीं माना गया कि नाटक के आखिर में शादी के प्रतीक के रूप में सिर्फ शहनाई और दुलहन की ओढ़नी का इस्तेमाल किया जाए. म्यूलर का कहना था कि अमेरिकियों को दूल्हा दिखाना जरूरी है ताकि उन्हें पता चले कि शादी हो रही है. इसलिए इस दृश्य में मंच पर दूल्हे की प्रतिच्छाया-सी दिखाते हुए शहनाई बजाई गई क्योंकि आखिरकार यह नाटक नेहरू और इंदिरा के बारे में है, पति-पत्नी यानी फीरोज और इंदिरा के बारे में नहीं. वैसे भी चिट्ठियों में फीरोज का जिक्र नहीं है.

एक अमेरिकी नाटककार के रूप में म्यूलर पिता और पुत्री के बीच के द्वंद्व को उजागर करती हैं जो कि नाटक के लिए महत्वपूर्ण है (इस मामले में बुद्धि और प्यार का भी द्वंद्व). अधिकार और यौवन के बीच

नाटक में पिता और पुत्री के बीच जो द्वंद्व दर्शाया गया है उसने इस नाट्यकथा को सशक्त बना दिया है

C... Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का यह द्वंद्व न सिर्फ नाट्यकथा को सशक्त बनाता है बल्कि इसकी वजह से नाटक, पीढ़ीगत अंतर से रोजाना रूबरू होने वाले अमेरिकियों के लिए अर्थवान भी हो उठा है. म्यूलर ने पुरानी खबरों की कतरनों में पढ़ा था कि नेहरू शादी करने के इंदिरा के फैसले से परेशान हो उठे थे. लिहाजा म्यूलर ने इंदिरा की चिट्ठियों में ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकीय अंदाज में उकेरा. मेहता के विचार से पिता-पुत्री के द्वंद्व के आसपास नाटक को केंद्रित करना और उसे शादी के साथ खत्म करना अमेरिकी शैली ही है. "इस विषय पर काम करने वाला कोई भारतीय या तो नेहरू परिवार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता या फिर कड़ी आलोचना, लेकिन पश्चिमी व्यक्ति हमारी तरह इस

भारत की आत्मा को म्यूलर ने बड़े चमत्कारी ढंग से पकड़ा. वे इसका श्रेय निर्देशक और पटकथा लेखिका मेहता को देती हैं

मुद्दे को इतने हल्के-फुल्के अंदाज में नहीं लेता. इस मुद्दे पर पिता-पुत्री के अलगाव को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाने का काम कोई एटनबरो या लवोन ही कर सकती हैं."

म्यूलर ने एक ऐसी हिम्मती लड़की का चित्रण किया है जो माता की रुग्णता और पिता के जेल में होने के बावजूद इलाहाबाद में अकेली ही 'जॉन ऑफ आर्क' का खेल खेलती है. इस स्थिति में किशोरी इंदिरा का अकेलापन, बोरियत और गुस्सा नाटक में साफ दिखता है ("इलाहाबाद कितना ऊबाऊ है. मैं फ्रांस में क्यों नहीं पैदा हुई? मैं 1200 ई. में क्यों नहीं पैदा हुई"). और जेल में बंद इतिहासकार पिता 'शिक्षा की अपर्याप्तता' की पूर्ति के वास्ते उसके लिए बौद्धिक जीवन का सृजन करते हैं.

म्यूलर की सबसे बड़ी उपलब्धि पिता और पुत्री का मानवीकरण करना है. वे इसे हास्य और काल्पनिक घटनाओं के प्रभावी निजी उद्बोधनों के जरिये दर्शाती हैं. मसलन नाटक में एक शानदार दृश्य है जिसमें इंदिरा ने अपने पिता के जन्मदिन का एक निहायत निजी आयोजन किया है. पिता और पुत्री दोनों पहले से ही तय समय पर एक साथ दीया जलाते हैं और मिठाई खाते हैं. नेहरू जेल की कोठरी में और इंदिरा आनंद भवन में. एक दूसरे मौके पर, अपने में खोई रहने वाली किसी भी साधारण किशोरी की तरह इंदिरा पिता से पूछती है, "पापू, क्या मैं सुंदर हूं? क्योंकि यदि मैं कुरूप हूं तो शेक्सपियर का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं." एक और मौके पर क्रुद्ध इंदिरा पिता पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया है और दरअसल वे जेल में ही रहना चाहते हैं. यह शिकायत करते हुए कि "आपने भारत के लिए बहुत कुछ कर लिया है" वह मांग करती है कि उन्हें

मार्था होल्मन

एक वास्तविक पिता होना चाहिए. नेहरू जवाब देते हैं, "मैं तुम्हारा पिता हूं. यह दीगर बात है कि मैं भारत के लिए क्या करता हूं." लेकिन इंदिरा तो चाहती है— "एक संपूर्ण पिता जो मुझे कागज की नौकाएं बनाकर दे." "तुम कागज की नाव चाहती हो? तुमने तो मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम कागज की नौकाएं चाहती हो!" इंदिरा बड़बड़ाते हुए कहती है, "मैं... मैं आपको किसी भी तरह कभी देख नहीं पाती." नेहरू आश्वासन देते हैं, "हम दोनों के पास एक-दूसरे की चिट्ठियां तो हैं ही..." इंदिरा जवाब देती है, "मैं चिट्ठियों के साथ साइकिल चलाने तो जा नहीं सकती, मैं चिट्ठियों के साथ छुट्टियां तो मना नहीं सकती." और इस तरह की बातें चलती रहती हैं जो इस विशिष्ट टिप्पणी के साथ खत्म होती है, "सदियों के अपमान और दमन के बाद इंदु, तुम्ही भारत की नई आत्मा, उत्साह और रोष हो. हो सकता है कि मैं तुम्हें घुमाने या साइकिल की सवारी के लिए न ले जा सकूं, लेकिन मैं तुम्हें 20वीं शताब्दी जरूर दूंगा." दूसरे माता-पिता इस तरह की कौन-सी अपूर्व चीज देने के लिए कह सकते हैं?

आखिर में, म्यूलर प्यार पर एक शानदार द्वंद्व पेश करती हैं. इंदिरा कहती है, "मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह प्यार करना चाहती हूं." लेकिन नेहरू उससे कहते हैं, "तुम दूसरी लड़कियों से भिन्न हो. मैंने तुम्हें संघर्ष के लिए तैयार किया है." "आपने मुझे प्यार के लिए भी प्रेरित किया है, पापू क्या आपने मुझे टैगोर की कविताएं नहीं दी?" और अपने चरित्र के मुताबिक नेहरू चीख पड़ते हैं, "मैंने टैगोर की कविताएं तुम्हें राष्ट्रवाद समझने के लिए दी थीं!" इस तरह की बातें सांस्कृतिक भिन्नताओं से परे होती हैं और समझदार भारतीय तथा अमेरिकी दर्शक भावनाओं में बह गए.

इस नाटक को देखने वालों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय प्रतिक्रिया एक 12 वर्षीय भारतीय की रही जिसने इसे 'डायरी ऑफ एन फ्रैंक' के समतुल्य रखा: नेहरू ने इंदिरा को पहली चिट्ठी उनके 13वें जन्मदिन पर लिखी और एन की डायरी भी उसके 13वें जन्मदिन पर भेंट स्वरूप मिली थी. ये दोनों चीजें जेल में लिखी गईं और दोनों में ही एक युवा लड़की के निजी दृष्टिकोण से आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है. थिएटर जाने के शौकीन इस भारतीय ने पुस्तकालय से 'ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' की एक प्रति ली और दूसरे दिन फिर इसी नाटक को देखने पहुंचा. म्यूलर और मेहता के लिए यह उनके नाटक की सफलता का प्रतीक है.

—विभूति पटेल, न्यूयॉर्क से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया ओनिडा
इसे छू पाये तो बस एक ईर्षा भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्षा के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठा ले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा लीक लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'क्यूब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' कैबिनेट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के नज़र में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्षा मंडराती है आसपास। याद रखिये वो सुघड़-वाणी: अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश का कुन्डम गांव! शाम ढले, जब पंछी अपने नीड़ की ओर लौटते हैं, सुशीलाबाई भी अपने कर्मवीर पति की वापसी की राह देखती हुई अपनी नन्हीं-मुन्नी रजनी को बहलाती है। उसका नन्हा बेटा बलराम भी गौओं के साथ खेलता-कूदता लौटने वाला है। नन्हीं रजनी की किलकारियां उसे उस वक्त की याद दिलाती हैं... आज से ८ साल पहले जब उनका नया-नया ब्याह हुआ था और उन्होंने परिवार कल्याण के लिए नियोजन का संकल्प लिया था, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल रहे। आई टी सी ने उन्हें राह दिखायी...

कुन्डम की सुशीलाबाई।
नये ब्याह के हुलास के साथ इन्हें चिन्ता थी
कि इनकी नियति छः बच्चों के बोझ से
थकी-टूटी इनकी माँ जैसी न हो।

तभी आई टी सी के
माध्यम से इनके पति ने परिवार नियोजन
साधनों को अपनाया।

'छोटा परिवार, सुखी परिवार' की जागरूकता

सन् १९६८ से आई टी सी भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल हुई और विस्तृत वितरण व्यवस्था एवं मार्केटिंग तजुर्बों के माध्यम से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश... अब दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश तक में निरोध के साधनों का प्रचार-प्रसार कर रही है।

भारत में निरोध-साधनों की सबसे बड़ी वितरक के रूप में आई टी सी ने खासतौर पर यह कोशिश की है कि देश के लोगों में छोटे परिवार के फ़ायदों के प्रति जागरूकता बढ़े।

सन् १९८९-९० तक यह कंपनी जन शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम और निरोध-साधनों के प्रचार योजना पर करीब १ करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करेगी।

सरकार के फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के सहयोग से आई टी सी इतने सारे इलाकों में कार्यरत है, जहां भारत की आधी आबादी रहती है। कंपनी ने उन रूढ़िवादी अंधविश्वासों के उन्मूलन की भी चेष्टा की है, जिसने देश की अधिकांश आबादी को मोहग्रस्त कर रखा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मनुष्य को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य में आई टी सी के प्रयास :

कृषि उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल-बीजों के उत्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार किसानों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी ।

भारतीय शास्त्रीय संगीत : कलकत्ते के संगीत रिसर्च अकादमी में परम्परा और तकनीक के गठबन्धन द्वारा आई टी सी ने गुरु-शिष्य परम्परा को जीवित रखा है और देश भर में नयी-नयी संगीत-प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है।

कार्पेट-उद्योग : शाहजहांपुर में आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के ज़रिए कालीन-बुनाई उद्योग को पुनर्जीवित किया ताकि २५०० से भी ज्यादा परिवार बेहतर कमा सकें, बेहतर जीवन जी सकें। कालीन निर्यात द्वारा आई टी सी विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है।

Contract ITC 57 88 HN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Agrawal Classes

A Picture of Success

Principal G.D. Agrawal with some of our top rankers in the I.I.T. JEE, 1988, at the 34th Annual Prize Distribution Functi

Sitting (Left to Right)

A Raghava Chari	1st
Bhaskar Himatsingka	3rd
Ashvin Goel	4th
Sudeep Gupta	5th
Sanjay Nayak	7th
G D Agrawal (Principal)	
P G Agrawal (Director)	
Sudesh Kamath	8th
C R Satyan	9th
V Bhargavan	10th
Navin G Kabra	14th

Standing (1st Row)

Venkat Krishnamurthy	15th
Rizwan R Koita	16th
K Srikanth	17th
Rajeev Barua	18th
Karl F Dias	20th
Manohar Moorthy	21st
Rakesh Garg	22nd
Sujoy Basu	23rd
Avnish Singh Bajaj	24th
Tushar S Desai	25th
Pandurang Katti	26th
C Sridhar	27th
Amol S Dighe	28th
Ankur Agarwal	29th
Manoj K Das	30th

Standing (2nd Row)

Vikas Vats	31st
M Kannan	32nd
Ruchir Godura	33rd
Rajesh Kamath	34th
Alok Goyal	35th
Lacky V Shah	36th
P Srinath	37th
Rajiv Chopra	38th
L B Hari Krishna	40th
Ajay Subramanian	41st
V Srinivasan	43rd
Ajit Bhave	44th
S Narasimhan	47th
Neil S Thombre	48th
R Rajesh	50th

Standing (3rd Row)

Roshan B Yadav	51st
R Prashanth	52nd
R Ramachandran	53rd
R Gopalakrishnan	54th
K N Ravi	56th
Shantanu S Tarafdar	58th
Udar Mittal	59th
Dhritiman Banerjee	60th
Manish Singhal	61st
Manish Khettry	62nd
Neeraj Aggarwal	63rd
V Venkatesh	65th
Arun Rangaraju	66th
Shyam Kapoor	69th

Standing (Top Row)

Sanjay S Singal	71st
Sandipan Basu	72nd
R Rajesh	75th
V Ramasubramaniam	77th
Shishir Tyagi	78th
Pradeep Gupta	79th
Shashidhar Gundurao	80th
Arpan P Mahorowala	83rd
S Narayanan	85th
B Venkata Vasu	
M S Jayashankar	
Anand Kishor	
S Srikant	
V G Prem Kumar	
B Srihari	
Shailesh Kumar	
Saurabh Tewari	

Absentees

Neeraj Sinha
S Ramesh
Rakesh Verma
S Manoj Kumar
R Srikrishna
Manish Rastogi
L Srinivas
Vibhuti Nath Mishra
Abhijit Belapurkar
Pinaki Ghosh
Anshuman Goyal
M Sridhar
R Kumaresan

Heartiest congratulations to our high-scorers in the I.I.T. JEE, 1988.

Once again, we've honoured the trust placed in us by our students. This year the All-India First is our scholar and eighty-three of our students have ranked within the first hundred in the General Category. Infact, today, 55% of the candidates selected I.I.T.s benefit from our comprehensive coaching. Which our reputation for ensuring excellent results.

Top-ranking students almost always come from Agrawal Classes!

Agrawal Classes

Wallace Apts. 3, N. Bharucha Marg,
Bombay 400 007

- For admission to our correspondence course for the I.I.T. JEE, 1990, contact us in December, 1988 with a xerox copy of your Std. X marksheet.
- Now, we also coach for CBSE's All-India PM/PO

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लॉन टेनिस

नई उम्र की नई फसल

लेकिन महंगे विदेशी सामान के कारण खेल आम नहीं

पिछले महीने सरगर्मी तो विंबलडन में थी लेकिन बुखार देश के नौजवानों पर चढ़ा हुआ था. टेनिस क्लबों की सदस्यता, योनेक्स टी शर्ट, डनलप रैकेट, माथे पर बांधी जाने वाली पट्टियां पाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा नौजवान उत्सुकता दिखा रहे थे. लॉन टेनिस अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि युवाओं की इस नई प्रवृत्ति को संतुष्ट कैसे करें.

देश के टेनिस क्लबों के अधिकारी टेनिस की अचानक बढ़ी लोकप्रियता का लगभग समूचा श्रेय दूरदर्शन को देते हैं. उनका मानना है कि विंबलडन और इससे पहले डेविस कप जैसे अहम मुकाबलों को छोटे पर्दे पर काफी वक्त मिलने के कारण नौजवानों में टेनिस के प्रति आकर्षण बढ़ा है. दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (डीएलटीए) के अवैतनिक सचिव यशवंत सिंह कहते हैं, "इसी अप्रैल में हमने प्रतीक्षा सूची में करीब 500 लोगों को सदस्यता दी है. लेकिन इस सूची में अब फिर 300 नाम हो गए हैं. लगता है मैं तो इसका निबटारा करते-करते पगला जाऊंगा."

आंध्र प्रदेश लॉन टेनिस एसोसिएशन के अधिकारी राजा नरसिंह राव के मुताबिक हैदराबाद में टेनिस का बुखार इस कदर चढ़ा कि एसोसिएशन को अपने टेनिस कोर्टों की संख्या इस साल के आखिर तक दुगुनी करने की योजना बनानी पड़ी. और इस तरह अपने कोर्टों की संख्या 14 तक करने का फैसला करना पड़ा. मशहूर बिलियर्ड खिलाड़ी माइकल फरेरा बंबई का हाल बताते हैं, "अभूतपूर्व उत्साह है. शहर के सभी टेनिस कोर्ट बुक हो गए हैं इसलिए रोजाना खेलने के लिए किसी खिलाड़ी को बमुश्किल 30 मिनट ही मिल सकते हैं." फरेरा का बेटा मार्क भारतीय लॉन टेनिस का उभरता सितारा है.

सभी महानगरों के अमूमन सभी क्लबों की प्रतीक्षा सूचियों में हजारों नाम दर्ज हैं. और इनमें अभी और इजाफा होने की उम्मीद है. दिल्ली जिमखाना में हाल तक टेनिस के प्रभारी रहे रवि कठपालिया के मुताबिक अब तक क्लब में रविवार को भी एक साथ आठ कोर्टों में ही खेल होता था लेकिन अब इस मौसम में भी 12 कोर्टों पर खेल चलता है. नतीजतन कोई भी कोर्ट ज्यादा वक्त खाली नहीं रह पाता.

प्रबंधकों और प्रशिक्षकों का कहना है कि देश के प्रचार माध्यमों में टेनिस को पहले के मुकाबले ज्यादा जगह मिलने की वजह से लॉन टेनिस के प्रति बढ़ती ललक और तेज हुई है. पिछले तीन वर्षों से युवक क्रिकेट के बाद टेनिस की ओर सर्वाधिक आकृष्ट हुए हैं. भारत के पूर्व डेविस कप खिलाड़ी एस.पी. मिश्र कहते हैं, "विंबलडन के टीवी प्रसारण और इस खेल से मिलने वाली ख्याति और पैसा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लुभाता जा रहा है."

ऐसा नहीं कि टेनिस खेलने का फैशन चल पड़ा है इसीलिए नौजवान इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं. प्रतिस्पर्धात्मक टेनिस में युवाओं की खासी दिलचस्पी तो साफ नजर आ रही है. मसलन बंबई में पिछले तीन साल में सब-जूनियर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 16 साल से कम के लड़के-लड़कियों की संख्या दस गुनी हो गई है. अमेरिका की प्रसिद्ध विटास गुरलाइटिस अकादमी, फ्लोरिडा से संबंधित जाने-माने भारतीय प्रशिक्षक प्रकाश राय कहते हैं, "पहले सब-जूनियर सिंगल्स टूर्नामेंट एक दिन में निबट जाते थे. लेकिन अब तो पहला चक्र ही कुछेक दिनों तक चलता रहता है." इसी तरह डीएलटीए की स्पर्धाओं की संख्या भी चार वर्षों में बढ़कर तिगुनी हो गई है.

इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविरों की संख्या बढ़ रही है और उनका स्तर सुधर रहा है. मद्रास में विजय अमृतराज ने ब्रिटानिया उद्योग के सहयोग से 'बैट' (ब्रिटानिया-अमृतराज टेनिस एकेडमी) की स्थापना करके इसका श्रीगणेश किया था. अब पूर्व राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन एनरिको पिपरनो ने भी बंबई में एक कंपनी प्रोकेम इनकारपोरेटेड बनाई है. प्रकाश राय के साथ वे विभिन्न शहरों में घूम-घूमकर युवाओं को प्रशिक्षण देंगे. वे खिलाड़ियों की फिटनेस और उनमें आक्रामक क्षमता उत्पन्न करने पर खास ध्यान देंगे क्योंकि आक्रामक क्षमता न होना ही भारतीय खिलाड़ियों की खास कमी रही है. पिछले पखवाड़े बंबई में 32 प्रशिक्षुओं के पंजीयन के साथ यह योजना शुरू हो गई. कलकत्ता में पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षक अख्तर अली और जयदीप मुकर्जी ने बाटा के सहयोग से एक शिविर चलाया है. दिल्ली में पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी असीम खेत्रपाल और पूर्व डेविस कप खिलाड़ी बलराम सिंह ने 1.5 करोड़ रु. के बजट से रेडीएंट टेनिस अकादमी शुरू की है. लॉन टेनिस में महारत हासिल कराने की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोटो: जगन्नाथ नेगी

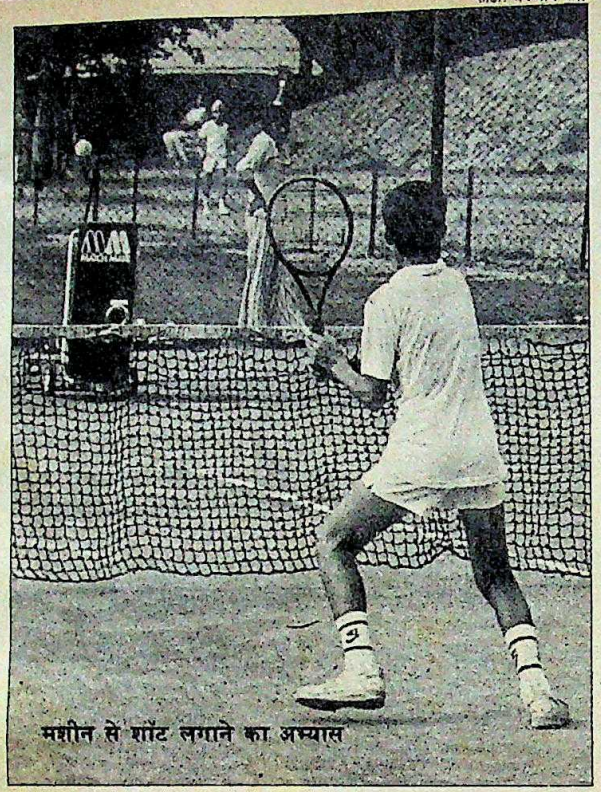

मशीन से शॉट लगाने का अभ्यास

यह योजना सात साल की है. उनके प्रयत्नों के परिणाम अभी से दिखने लगे हैं. अकादमी के एकदम नए 25 प्रशिक्षु दिल्ली के टेनिस हलके में अपनी मौजूदगी दिखाने लगे हैं. डीएलटीए ने तो अपने प्रशिक्षुओं की मदद के लिए गेंद फेंकने वाली मशीन तक लगा ली है.

निजी कोर्टों की संख्या में भी इजाफा हुआ है क्योंकि दिल्ली के बाहरी इलाके में बने फार्म हाउसों के मालिक अपने खुद के कोर्ट बना रहे हैं. खेल के सामान के व्यापारी चेतन सिंह बताते हैं, "हर साल तकरीबन 20 से 30 निजी कोर्ट बन रहे हैं." जाहिर है, इस लोकप्रियता का लाभ उनके जैसे विक्रेताओं को सबसे ज्यादा हुआ है. दिल्ली में सायमंड्स के वितरक आर. गुप्ता कहते हैं, "एक साल पहले मैं टेनिस के तकरीबन 300 दर्जन गेंद बेचा करता था लेकिन अब मैं 500 दर्जन गेंद बेचता हूं." महाराष्ट्र लॉन टेनिस एसोसिएशन के सचिव और पहले टेनिस के गेंद बनाने वाली कंपनी के मालिक रहे रमेश देसाई बताते हैं, "बारह साल पहले महाराष्ट्र में सालाना मांग 1,000 गेंदों की थी. अब 40,000 गेंदों की मांग हो गई है."

साधारण आयातित रैकेट तकरीबन 750 रु. का पड़ता है. लेकिन डनलप, डॉनी, हेड ऐंड प्रिंस सरीखे युवाओं के पसंदीदा रैकेट 1,200 रु. से ज्यादा के पड़ते हैं. सायमंड्स के भारत निर्मित गेंद की कीमत 20 रु. है. लेकिन पेन और डनलप सरीखे उम्दा विदेशी गेंदों की कीमत इसकी तकरीबन तीन गुनी पड़ जाती है.

इसके अलावा क्लबों की तगड़ी फीस में कमी की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती. निजी क्लबों की फीस तो मध्यम वर्ग की पहुंच के बाहर ही है और सार्वजनिक टेनिस कोर्टों की संख्या इतनी कम है कि उनसे कोई मतलब हल नहीं होता. दिल्ली के चारों सार्वजनिक टेनिस कोर्ट जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हैं.

डीएलटीए ने तीन नए कोर्ट बनाने की पहल की है. लेकिन एक अनुभवी खिलाड़ी के मुताबिक ये कोशिशें स्वीडन और पश्चिम जर्मनी के टेनिस संघों के प्रयासों के मुकाबले बेहद धीमी और असंगठित हैं—बिलकुल बोरिस बेकर की तेजतर्रार सर्विस के मुकाबले रमेश कृष्णन की सर्विस की तरह.

इस सबके बावजूद टेनिस आम जनता का खेल कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसके कम खर्चीले होने की कोई उम्मीद नहीं. स्वदेशी सामान अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं होता और तस्करी से आया तथा आयातित विदेशी सामान बहुत महंगा पड़ता है. एक

—महेश कृष्णमूर्ति और सलिल त्रिपाठी

प्रशिक्षण शिविर

बच्चों का बल

पुराने खिलाड़ियों को शायद ही याद होगा कि बंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) के टेनिस कोर्ट पर इतना उत्साह, इतना जोशो-खरोश उन्होंने कब देखा था. मैदान पर रंग-बिरंगी झंडिया लहरा रही थीं मानो कोई उत्सव हो रहा हो. और इसी माहौल में भावी स्टीफन एडबर्ग और बोरिस बेकर रैकेट घुमा-घुमा कर गेंद पर शॉट लगा रहे थे. उनके प्रशिक्षक उन्हें ऐसे शॉट लगाने का अभ्यास करा रहे थे जो उनकी नन्ही भुजाओं के हिसाब से नामुमकिन ही लग रहे थे. लेकिन दस साल आयु वर्ग की नंबर दो खिलाड़ी नौ वर्षीया जाह्नवी पारेख ने बेस लाइन के उस पार तक दौड़ते हुए गेंद को चकरघिन्नी खिलाने वाला जो फोरहैंड शॉट मारा उसकी तो शायद जाह्नवी की आदर्श मार्टिना नवरातिलोवा भी तारीफ करतीं.

पर फिलहाल तो उसे भारत के पूर्व जूनियर चैंपियन एनरिको पिपरनो और फ्लोरिडा की विटास गुरलाइटिस अकादमी में आठ साल प्रशिक्षक रहे प्रकाश राय की तारीफ भरी मुस्कान ही मिली. पिछले पखवाड़े पिपरनो और राय ने बंबई में प्रशिक्षण शिविर शुरू किया.

फिलहाल तो बंबई की बारी है. राय ने जब देखा कि जाह्नवी एक स्ट्रोक नहीं खेल पाई तो उन्होंने मुस्कराते हुए उसे बताया कि गलती कहां हुई. लेकिन राय की नजरें तेजी से पूरे मैदान पर घूमती हैं और वे सबको हिदायत देते हैं, "जमीर, तुम्हारा फॉलो-थ्रू ठीक नहीं है. साहिल, कोर्ट में आकर इस शॉट को कमर की ऊंचाई से खेलो. प्रियंका, तुम्हारे पैर ठीक से नहीं पड़ रहे. अपने पैरों को उचकाओ...हां, यह अच्छा शॉट है."

शॉट न लगा पाने पर एक बच्चा तर्क देता है, "सर, गेंद बहुत दूर थी." राय एक सख्त प्रशिक्षक की तरह उससे कहते हैं, "अगर तुम गेंद से दूर रह गए, तो समझो कि मारे गए."

उनके ज्यादातर प्रशिक्षणार्थी आठ से 15 साल की उम्र के राज्यस्तरीय या राष्ट्र स्तरीय खिलाड़ी हैं. प्रशिक्षार्थियों में से प्रत्येक ने छह दिनों के इस शिविर के लिए 1,500 रुपए दिए हैं. पिपरनो मानते हैं कि वे सब अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल रहे हैं. वे कहते हैं, "प्रतिस्पर्धा वाले टेनिस के खिलाड़ी में वह दमखम होना चाहिए जो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी, बाधा दौड़ या फर्राटा दौड़ या मध्यम दूरी के धावकों में होता है." इस शिविर में उभरते खिलाड़ियों में इस तरह की क्षमता का विकास करने पर जोर दिया जा रहा है. —सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'चौराहा'

कुव्यवस्था पर कटाक्ष

मौजूदा समाज की कुरूपताओं और हताशा का चित्रण

"खंडित! ... जरूरत है एक ऐसे देश की जो हमें गुलाम बनाकर हमारे देश का शासन अच्छी तरह कर सके..." यह घोषणा जारी करने वाले वे लोग हैं जो खुद तो हड़ताल, हिंसा और गैरजिम्मेदारी के बूते पर कुव्यवस्था फैलाए हुए हैं लेकिन देश से यह अपेक्षा लगाए हैं कि वह ठीक से चले. राजधानी की 'सूत्रधार' नाट्य मंडली द्वारा पिछले पखवाड़े श्रीराम केंद्र में मंचित नाटक 'चौराहा' ऐसी तेजाबी चुटकियों से भरा पड़ा है. देव तनेजा के निर्देशन में जम्मू और कानपुर के बाद दिल्ली में पहली बार पेश किया जाने वाला यह नाटक रंग आंदोलन की उस धारा का प्रतिनिधि है जो मौजूदा समाज की कुरूपताओं, विसंगतियों और विडंबनाओं को उसके नंगे रूप में पेश करने की दिशा में बहती है.

इस नाटक में लेखक सुदर्शन मजीठिया ने मंच को सचमुच के एक ऐसे चौराहे का रूप देने का प्रयास किया है जहां युवा असंतोष और मजदूरों के आंदोलन से लेकर राजनैतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुव्यवस्था, कुशासनहीनता, सांप्रदायिकता, हिंसा, अलगाववाद, भूख और हड़ताल जैसी सारी समस्याएं एक के बाद एक अपना रौद्र रूप दिखाती हैं. बीच-बीच में सूत्रधार (राजेश पुरी) मंच पर आता है और घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों और वर्गों पर अपनी टिप्पणियां करता है. सूत्रधार की अधिकांश टिप्पणियां पंडित हरिकांत के कथा संग्रह 'एक टुकड़ा इतिहास' से ली गई हैं जो कुछ स्थानों पर तो राजनीति, राजनेताओं और कुव्यवस्था के जिम्मेदार लोगों पर तेजाबी हमला करती हैं:

"कल जो उधार ले गए थे हमसे हमारा कद, सभी सीढ़ियां छोटी पड़ गई हैं आज उन तक पहुंचने के लिए... अपने हिस्से का सच झुठलाकर इतने बौने बन गए हैं आज कि सर्कस में जोकरों की कुल संख्या 500 है 90 करोड़ दर्शकों का मनोरंजन करते हैं इस अनुपात की आलोचना देशद्रोह कहलाएगी! आखिर यह सर्कस बस्ती का सबसे निकृष्टतम पराक्रम है और संसार का सबसे बड़ा सर्कस है..."

एक अन्य स्थान पर देश की समस्याओं पर लंबा-चौड़ा भाषण देने वाले और जनता को शांति बनाए रखने की हिदायत देने वाले नेता जी पर कटाक्ष करते हुए सूत्रधार टिप्पणी करता है, "...भूख का भूगोल हम नहीं जानते! इसका क्षेत्रफल राजभवन या

'चौराहा' : अर्थपूर्ण मनोरंजन

फिर राज सिंहासन जितना होता है! पर हमें केवल इतना पता है कि हमारी भूख का क्षेत्रफल केवल रोटी जितना है..."

> **"कल जो उधार ले गए थे हमसे हमारा कद, सभी सीढ़ियां छोटी पड़ गई हैं आज उन तक पहुंचने के लिए"...**
>
> इसी नाटक का एक संवाद

सूत्रधार की ये टिप्पणियां नाटक को यकीनन एक खास दिशा में ले जाने का प्रयास करती हैं. लेकिन एक के बाद एक जिस तरह मौजूदा हिंदुस्तान की समस्याओं को गिनाने का प्रयास किया गया है वह कुछ स्थानों पर डॉक्युमेंटेशन की हद तक जाते हुए दर्शक की उत्सुकता को बनाए रखने में कमजोर पड़ने लगता है. लेकिन इस एकरसता को तोड़ने के लिए जगह-जगह विदूषक का प्रवेश काफी सफल रहा है. इसका श्रेय काफी हद तक विदूषक की भूमिका निभाने वाले अशोक कुमार के अभिनय को जाता है. अभिनय की दृष्टि से कुछ कलाकारों का बनावटीपन छिपाए नहीं छिपता पर उसकी एक वजह शायद भाषा का किताबी होना और उसकी संस्कृतनिष्ठ शुद्धता भी है.

नाटक में छाये रहने वाले उसके राजनैतिक चरित्र के पक्ष में तनेजा दलील देते हैं, "पिछले साल सूत्रधार की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई थी कि दर्शक को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण मनोरंजन उपलब्ध कराया जाए. 'चौराहा' भी इसी नजर से पेश किया गया है कि दर्शक अपने आसपास होने वाली घटनाओं और समस्याओं को गंभीरता से देखे और उनका हल निकाले."

नाटक का अंत पात्रों की इस सामूहिक टिप्पणी से होता है, "हम सब राहगीर हैं. हम भटक रहे हैं, थक चुके हैं. हमें मंजिल की तलाश है. हमें कौन रास्ता बताएगा?" इस हताशा भरी टिप्पणी के जवाब में रोशनी दो बच्चों पर केंद्रित हो जाती है जो हाथ में लाल झंडे लिये हुए हैं. तनेजा की नजर में लाल झंडे को क्रांति और आशा के प्रतीक के रूप में लिया गया है. पर यह दृश्य नई पीढ़ी में आशा की किरण दिखाने के बजाय पिछली पीढ़ी द्वारा अपनी असफलताओं को उसके कंधे पर डालकर छुट्टी पाने का प्रयास अधिक लगता है. —विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इमरान खां

साफगोई से परहेज

पाकिस्तानी क्रिकेट ऑलराउंडर ने कई सवाल अनुत्तरित ही छोड़े

ऑल राउंड व्यू
इमरान खां
चट्टो ऐंड विंडस
कीमत: 12.95 पाउंड ; कुल पृष्ठ: 210

यह युवा प्रेमियों की-सी किसी कहानी का नजारा है. कुर्सी पर अधलेटा, ख्यालों में खोया, लंबे कद और किसी एथलीट-सी काया वाला नायक, ब्लेड की तीखी धार से जगह-जगह छिला फिल्मी सितारों-सा उसका मुखड़ा, बेतरतीब बाल और सहारे के लिए दूसरी कुर्सी पर रखी उसकी एक टांग. उसी कमरे में उसका चित्र बनाती नायिका जो अपने क्षेत्र में उतनी ही विख्यात है जितना कि नायक अपने क्षेत्र में.

खेल के मैदान में वे स्टार ही नहीं, सुपरस्टार हैं. पर अब उनकी एक घायल टांग ने और ऊंचा उठने के उनके सपने चकनाचूर कर दिए हैं, एक के बाद दूसरी पराजय से उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ा है और डॉक्टरों के मुताबिक वे आइंदा कभी नहीं खेल पाएंगे. इमरान खां की जीवन गाथा हर लिहाज से एक परी कथा है. यह बात दीगर है कि वह हकीकत से भी मेल खाती है. सुख-वैभव में पले-बढ़े, दौलत और रुतबे से घिरे तथा बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा पाकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पहुंचे इमरान की भाग्य रेखा शायद ऊपरवाले ने अपने हाथों से ही उकेरी थी.

पर अड़चन यही है. उनके सनसनीखेज कैरियर में कल्पना और यथार्थ गड्डमड्ड हो गए हैं. असली इमरान खां कौन थे या हैं? एक रईस और बिगड़े रसिक जिन्होंने अपनी छवि और उपलब्धियों के बल पर खुद अपना कैरियर बनाने की सामर्थ्य हासिल की या एक समर्पित पेशेवर खिलाड़ी जिन्होंने अपने दौलत-मान पर कभी दंभ नहीं किया? एक निरंकुश और स्वार्थी कप्तान जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं दूसरों से कई गुना ज्यादा रहीं, या जन्मजात अगुआ जिनमें दूसरों को भी बड़े कारनामों के लिए प्रेरित करने की क्षमता रही?

अफसोस कि इमरान खां की हाल ही में प्रकाशित और बहुप्रतीक्षित आत्मकथा में इनके कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलते. भले ही इमरान की जीवन झांकी से रश्क करने वाले अनेक लोग हों और हर प्रकाशक उसे हाथो-हाथ छापने को उत्सुक रहा हो पर साहित्य के क्षेत्र में उनका पहला प्रयास बेहद निराशा-जनक रहा है. ऐसा क्यों हुआ, यह रहस्य ही है. उनके नाम में अभी भी इतना जादू है कि किताब हाथोहाथ बिक जाएगी. लेकिन यह उनकी इस मेहनत का फल नहीं होगा.

कुल मिलाकर यह किताब उनके क्रिकेट कैरियर का सीधा-सादा लेखा-जोखा है जिसमें

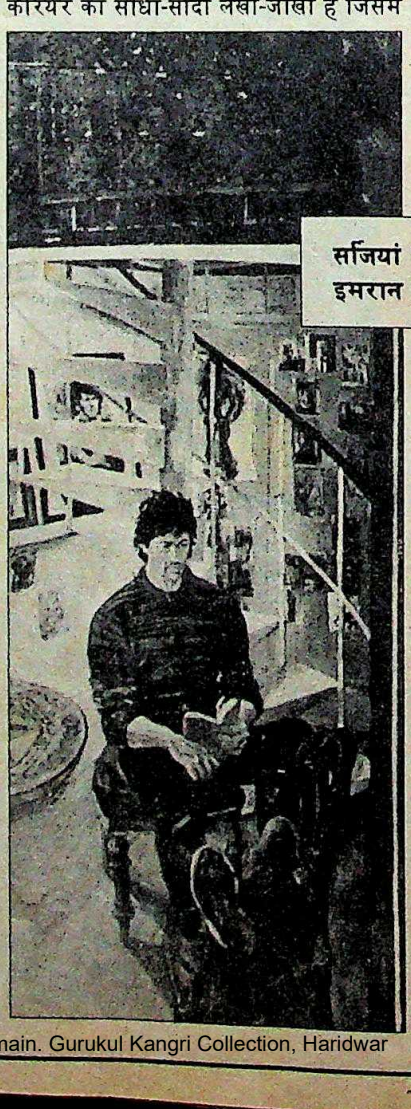

सजियां का बनाया इमरान का चित्र

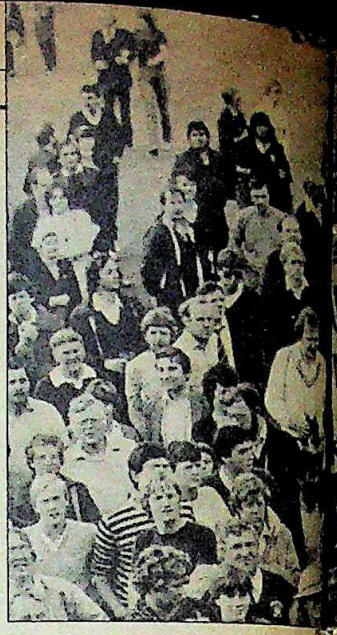

उनकी निजी जिंदगी के चंद पन्नों को सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया इसका एक प्रमुख उदाहरण अनेक महिलाओं से उनके कल्पित संबंधों इमरान बड़े रौब से बताते हैं कि रसिक छवि भाड़े के लेखकों की कल्पना भर थी. मशहूर चित्रकार सर्जियां को, जिनके इमरान के साथ को लेकर लंदन भर में चर्चा थी और ऐसी भी थीं कि दोनों ने शादी कर महज़ एक 'अच्छी मित्र' बताया गया

एक अध्याय को किताब में कहीं कोई नहीं उठाया गया है अध्याय में इमरान स्तान की क्रिकेट व्यवस्था और वहां के कंट्रोल बोर्ड को आड़े हाथों लेते हैं. पर वे अपनी साहित्यिक छवि ही चमकाते हैं. उनकी शिक्षा-दीक्षा के दिनों और स्तान में क्रिकेट व्यवस्था पर उनके वाले अध्यायों को छोड़ दें तो इस को क्रिकेट के आंकड़ों का कोई जानकार भी लिख सकता था. अपने विपरीत यह किताब इमरान के क्तित्व के बारे में कम, उनके खिलाफ के पक्ष को ज्यादा उजागर करती है.

इससे पता चलता है कि इमरान बहुत-से महत्वाकांक्षी क्रिकेट खिला तुलना में ज्यादा सुविधाएं हा निस्संदेह उनमें विशेष प्रतिभा किस्मत ने भी उनका ही साथ तेजी से वे प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला और फिर टेस्ट मैचों में (18 में) शामिल हुए उसका श्रेय जहां में निहित है कि उस समय पाकिस्तान बहुत कम तेज गेंदबाज थे, वहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

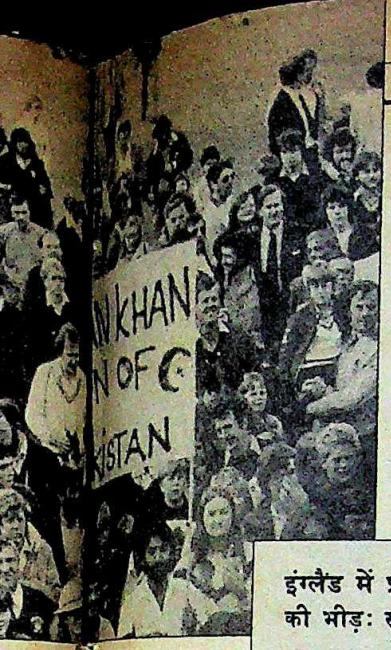

इंग्लैंड में प्रशंसकों की भीड़: सम्मोहन

...वंद पन्नों को ... परिवार का प्रभाव भी उनके काम ...ाल किया ... (उनके एक चाचा राष्ट्रीय चयन-...हरण अनेक ...ों में थे और परिवार के आठ सदस्य ...पत संबंधों ... श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी थे)

...ाते हैं कि ...हली बार टेस्ट मैच में भी इमरान ...लेखकों की ...म रहे थे पर सुविधाओं और किस्मत ने ...र चित्रकार ...बचाए रखा. उनके मां-बाप ने उन्हें ...ान के साथ ...ड के वारसेस्टर रॉयल ग्रामर स्कूल में ...र्ता थी और ...ल करवा दिया जहां उन्होंने अपनी खेल ... शादी कर ...भा इस कदर बढ़ा ली कि उन्हें ...बताया गया ...स्टरशायर काउंटी की दूसरी टीम ...अध्याय को ...ामिल कर लिया गया. उन्हीं के ...ं कहीं कोई ...बिक ऑक्सफोर्ड में भी उन्हें ...ाया गया है ...ला मिलने की बड़ी वजह यही ...में इमरान ...कि विश्वविद्यालय के पास कोई ...और वहां के ...दबाज नहीं था. मगर पांव जमा ...ं लेते हैं. पर ...के बाद उनकी स्वाभाविक प्रतिभा ...ही चमकाते ...ाई. इमरान ऑक्सफोर्ड में कप्तान ...दिनों और ...ुकने के बाद देश की टीम की ...पर उनके ...ों भी करने लगे. तेज़ गेंदबाजों ...दें तो इस ...ों में वे उस चोटी पर पहुंच गए ...का कोई ...हकारी अंदाज में उन्होंने खुद को ...था. अपने ...का सर्वोत्तम ऑल राउंडर ...रान के स... ...दे डाला.

...नके खिलाड़ी ...ताब में चलते-चलाते इमरान ...र करती है ...क्रिकेट में पैदा हुए उन गहरे ...कि इमरान ...ों को तसदीक भी करते हैं जिनकी ...केट खिला... ...पाकिस्तान को खेल के मैदान ...धाएं हा... ...नुकसान उठाना ...प्रतिभा ...मसलन ज़हीर अब्बास ...साथ दि... ...ानी के जमाने में खुद ...खिलाड़ी ...और जावेद मियां-...पहला मै... ...बीच 'खुली और गाली-गलौज ...(18 वर्ष ...ड़पें' होना; पूरी टीम द्वारा ...श्रेय जहां ...र की अगुआई में खेलने से ...पाकिस्ता... ...करने के कारण विद्रोह की ...थे, वहीं ...पैदा होना; ज़हीर का इमरान

को कप्तान पद से हटवाने की साजिशें रचना; और ज़हीर या इमरान में से किसी को भी कप्तान बना दिए जाने की सूरत में दोनों का एक-दूसरे की अगुआई में खेलने से इनकार कर देना.

लेकिन मैदान में दमदार खेल की तरह ही किस्मत भी दृढ़ता से उनके साथ चिपकी रही. वे मियांदाद और ज़हीर के झगड़े के चलते ही कप्तान बन पाए. फिर, कैरी पैकर के उपक्रम में शामिल होने के बाद इमरान को राष्ट्रीय टीम से हटा दिया गया तो किस्मत ने यहां भी साथ दिया. अगर मैच पाकिस्तान के कट्टर विरोधी भारत की क्रिकेट टीम के साथ न होता तो वे अपनी जिंदगी की बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट शृंखला में भाग लेने से वंचित ही रह जाते.

1980 में इमरान का कैरियर पुनः लड़खड़ा गया जब पाकिस्तान को भारत में हुई टेस्ट शृंखला में हार का सामना करना पड़ा और उनकी टांग टूटने की वजह से लगने लगा कि उनका खेल अब खत्म हुआ कि तब. उनकी हताशा उनके इस बयान से झलकती है, "पुराने वक्त के कई बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह मुझे भी बुरा-भला कहे जाने और तनहा छोड़ दिए जाने के बाद क्रिकेट से नाता तोड़ना ही था."

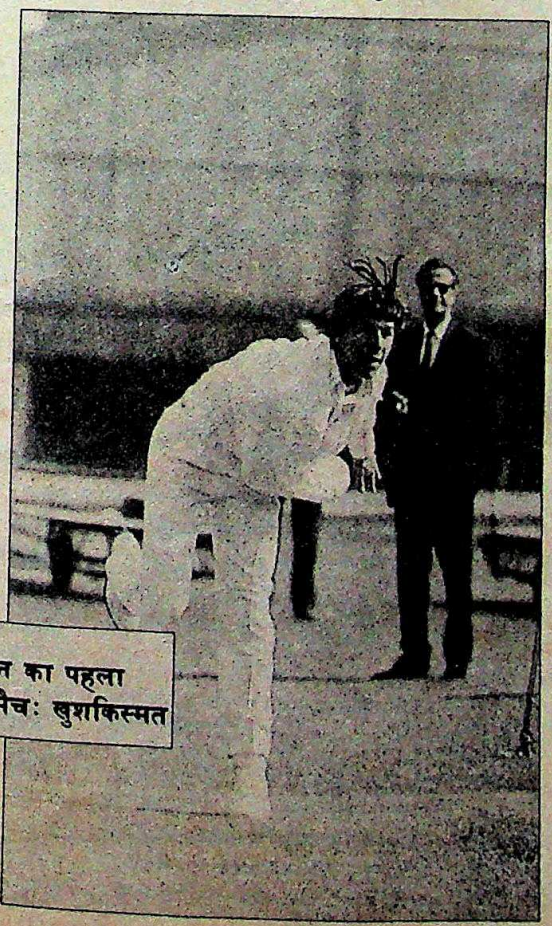

इमरान का पहला टेस्ट मैच: खुशकिस्मत

पर तनहाई उन पर गालिब नहीं हो सकी. इस बार किस्मत इमरान के सबसे बड़े संरक्षक पाकिस्तानी राष्ट्रपति ज़िया-उल-हक के रूप में प्रकट हुई. लंदन में उनकी टांग की सर्जरी पर हुए खर्च में पाकिस्तान सरकार ने भी हिस्सा बंटाया. उनके लौटने पर ज़िया ने और भी महत्वपूर्ण काम किया. उस समय मियांदाद पाकिस्तान के कप्तान थे. 1983 के कई टेस्ट मैचों में हारने के बाद पाकिस्तान को एक-दिवसीय मैचों में लगातार तीन बार भारत से मात खानी पड़ी थी. राष्ट्रपति ज़िया ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भारी फेर-बदल करवाकर कप्तान पद के लिए इमरान का रास्ता साफ कर दिया.

1987 का रिलायंस कप मैच खत्म होने के बाद जब इमरान ने टेस्ट मैचों से अलविदा लेने की सोची तो ज़िया ने उन्हें अपने फैसले पर गौर करने को कहा और वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच में कप्तान पद पर रहने के लिए मना लिया. वहां उन्होंने अपनी साख जमाई भी. उसी साख के बलबूते इमरान ने अपने क्रिकेट कैरियर के भविष्य का मुद्दा खुला छोड़ दिया. क्या उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है? इस सवाल पर कुछ कहने के बजाय उनकी मंशा कूटनीतिक ढंग से मामले को लटकाए रखने की है.

यह बात एक तरह से किताब की अस्पष्ट शैली के माफिक बैठती है जिसमें उनके क्रिकेट कैरियर के कुछ पहलुओं पर तो विस्तार से चर्चा की गई है मगर दूसरी अनेक बातों को छुआ तक नहीं गया. इमरान इस उपमहाद्वीप के प्रतीक पुत्र के रूप में सामने आए हैं. अपने देश के प्रति प्यार और उस पर गर्व होने के बावजूद वे वहां की व्यवस्था और उसकी खामियों से घृणा करते हैं. अपनी पठान वंश परंपरा के अनुरूप वे बेहद स्वाभिमानी हैं पर साथ ही अपने मां-बाप की इच्छाओं के पूरी तरह अधीन हैं (मसलन मां-बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करने से उनका इनकार).

यह साफ है कि इमरान सितारों सरीखी उस हैसियत के मालिक हैं जो पूरी किताब में छायी उनकी विनम्र भावना से मेल नहीं खाती. पर यह भी सच है कि इस हैसियत का इमरान से ज्यादा और कोई हकदार नहीं. लिखते वक्त अगर उन्होंने यह ध्यान में रखा होता तो यह किताब यादगार बन सकती थी.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिर्फ़ प्यार ही नहीं चुका सकता इनकी दवाओं के बिल.

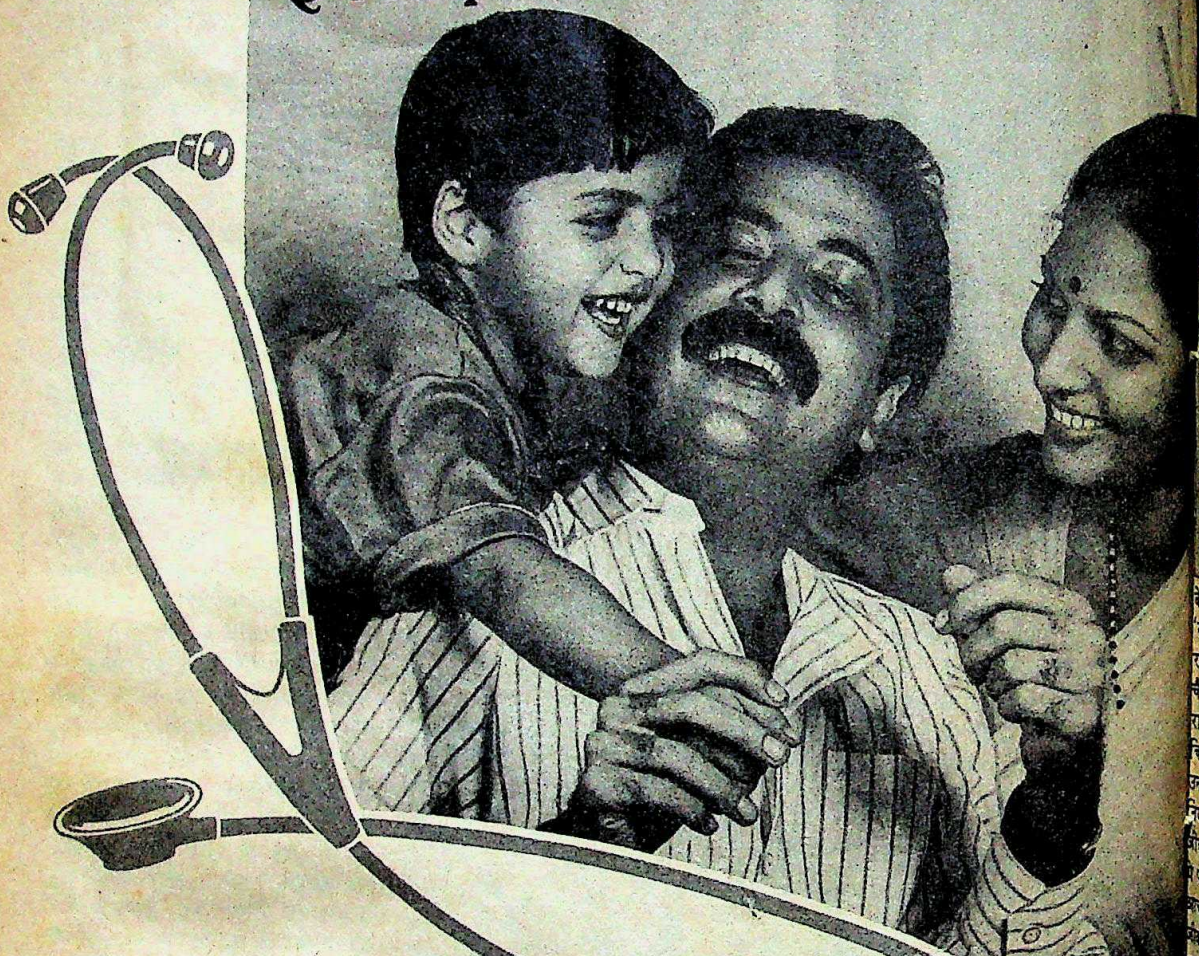

इसके लिए चाहिए मेडिक्लेम.

जी हां, मेडीक्लेम की हॉस्पिटलाइज़ेशन और डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन बेनिफ़िट पॉलिसी आपके परिवार के लिए है एक अनोखा वरदान.

आपका ढेर सा प्यार...आपकी कंपनी की कोई भी मेडीकल योजना.... बड़ी-बड़ी बीमारियों, ऑपरेशन और दुर्घटना में इलाज पर होने वाले खर्च का बिल नहीं चुका सकती.

इसीलिए आपको चाहिए मेडीक्लेम. मेडीक्लेम के ज़रिए आप कई तरह के चिकित्सा लाभ हासिल कर सकते हैं– वह भी आपकी आवश्यकता, आपकी ज़रूरतों के अनुरूप.

यहां तक कि आप घर पर रहकर इलाज करने का खर्च भी पा सकते हैं.

साथ ही आप पारिवारिक-छूट और करों में छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.

यदि आप अपने परिवार को सही मायने में प्यार करते हैं तो मेडीक्लेम योजना के अंतर्गत इनका बीमा कराइए.

जो आपको कम खर्च में दिलाए कहीं ज़्यादा सुरक्षा, कहीं ज़्यादा लाभ और यही है आपके प्यार का सच्चा सुबूत.

प्रीमियम प्रति वर्ष रु.	हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.	डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.
२००	१०,५००	३,१००
२५०	१७,६००	–
३५०	२५,५००	–
६०० *	३७,७५०	५,२५०
८४० *	५२,७५०	७,४००
१,३०० *	८२,५००	११,५००

आयु सीमा ५ से ७० वर्ष

★ *अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने पर व्यक्ति दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध.*

MEDICLAIM

मेडीक्लेम के प्रस्तुतकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस

NEW INDIA ASSURANCE

A subsidiary of the General Insurance Corporation of India

खतरे का कोई भी नाम... बीमा करना हमारा काम.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहानी संग्रह

हकीकत से परे का सच

नियति नहीं बल्कि व्यवस्था से अभिशप्त जीवनों की गाथाएं

भविष्य तथा अन्य कहानियां
[illegible] भटियानी
कुल पृष्ठ-141, कीमत 50 रु.
मुद्रित प्रकाशन, 109, रिछपालपुरी
[illegible]बाद (उ.प्र.)

ये कहानियां उस यथार्थ को उद्घाटित करने का प्रयास करती हैं जो सामान्य जीवन से बाहर का है. 'चील' कहानी के बारह-तेरह वर्ष के चोर रामखिलावन; 'मैमूद' कहानी की बकरे को बेटे की तरह प्यार करने वाली जद्दन; 'रहमतुल्ला' कहानी के लावारिस बालक रहमतुल्ला; 'महाभोज' कहानी के शराबी चैतीराम और 'भविष्य' कहानी के राहजन राधे काछी की जिन जीवन-स्थितियों का चित्रण इस कहानी संकलन में किया गया है, उनके जिस दुःख-दर्द को इन कहानियों में उकेरा गया है, सामान्य जीवन में उससे वास्ता नहीं पड़ता. ये पांचों कहानियां आम सामाजिक आचार-व्यवहार से विमुख पात्रों की जीवन-स्थितियों की कहानियां हैं, हालांकि उनके इस तरह जीवन जीने के पीछे के कारण सामाजिक व्यवस्था में ही निहित हैं. लेखक ने तटस्थ रहते हुए इन अनैतिक किस्म के लोगों की दुनिया की वास्तविकताओं और दुख-दर्द को इन कथाओं में चित्रित किया है.

'चील' कहानी का रामखिलावन बारह-तेरह वर्ष का है, उसका बाप मर चुका है. उसे याद है कि उसका बाप "अक्सर पत्नी के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर लौटता था और गंदी-गंदी गालियां बकता हुआ चौकी पर लुढ़क जाता था. उसकी दादी [illegible] झलकर मक्खियां हटाती हुई, धोती के [illegible] से अपने बेटे के नशे में खिंचे हुए-से [illegible] में लगी गंदगी को पोंछ देती थी." इस [illegible] के बाप का बेटा यदि सड़क पर पड़े [illegible]-सिगरेट के टोटे उठाकर पीता है और भूख की मार से ग्रस्त होकर बार-बार चोरी कर लेता है, तो अस्वाभाविक नहीं. अलबत्ता छोटी उम्र में ही वह समझ चुका है कि "उसकी मां सतनारायनी बुरादे में लपेटी हुई बर्फ की सिल्ली की तरह धीरे-धीरे गलती आई एक औरत! बच्चे जनती हुई.... शुक्र है रामखिलावन के अलावा उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा."

पूंजीवादी व्यवस्था और उपभोक्ता संस्कृति के चलते मौज मार रही भद्रजन संस्कृति के सामने जीवन का नरक भोगते लोगों का यथार्थ 'रहमतुल्ला' कहानी में प्रस्तावित है. रहमतुल्ला दो-ढ़ाई बरस का लावारिस बालक है जिसके मां-बाप गुजर चुके हैं. उसकी मां हिंदू थी जिसने भागकर मुसलमान से शादी कर ली थी. उसका मामा उदेराम अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर उसे अपने यहां ले आता है. लेकिन बिरादरी मुसलमान के लड़के को घर में रखने की सजा के बतौर उसका हुक्का-पानी बंद कराने की धमकी दे देती है.

> **"...यह भविष्य है जो अपने भीतर के अंधेरे में हिंस्र जानवर की आंखों की तरह चमकता रहा है. इसको इससे ज्यादा अपने अस्तित्व में अनुभव किया नहीं. पांवों के सामने पड़ा वक्त ही गिद्धों की तरह कंधों पर बैठ जाता रहा है."**
>
> **इसी संग्रह से**

उदेराम रहमतुल्ला को लावारिस छोड़ देता है और देश का यह नौनिहाल सड़कों-गलियों में रेंगने के लिए अभिशप्त हो जाता है.

'महाभोज' का चैतीराम कोई भी धंधा न करने वाला शराबी है. उसकी पत्नी शिवरत्ती चार बच्चे जन चुकी है और पांचवां पेट में है. बाप के मरने पर चैतीराम, जिसकी हैसियत बिरादरी में गुड़ बांटने की भी नहीं है, भोज कहां से दे. उसकी पत्नी को अपनी करधनी बेचनी पड़ती है. "सारी बिरादरी अपने-अपने घरों को वापस लौटने लगी, तो शिवरत्ती को इतना संतोष जरूर अनुभव हुआ कि चलो, चौबीस घंटे कमर पर रहने वाली पचास तोले की करधनी तो गई मगर पितरों का ऋण निबट गया."

'भविष्य' कहानी पैंतालीस वर्ष तक भविष्य तलाशते राहजन राधेश्याम काछी की कहानी है जो हमेशा वर्तमान में बने रहने को अभिशप्त रहा. "अपनी अपराधी और भविष्यशून्य जिंदगी के प्रति दहशत और वितृष्णा के क्षणों में न जाने कितनी बार आत्महत्या कर लेने की बात उसकी कल्पना में उभरी है." कहानी के अंत में उसे विधवा शांति अहीरन के साथ अपना भविष्य नजर आने लगता है. लेकिन वैसा शराब के नशे में होता है. शांति अहीरन भी पी रही होती है. अतः यह पक्का विश्वास नहीं होता कि राधे काछी का पैंतालीस बरस की उम्र में कोई भविष्य बन जाएगा.

'इतिहास' कहानी की कथावस्तु उक्त कहानियों से अलग किस्म की है. यह कहानी बीते बचपन की स्मृति और पहाड़ी जीवन में आए बदलाव की कहानी है. उप्रेती साहब बीस वर्ष बाद पत्नी और पोते के साथ अपनी गाड़ी में गांव लौटते हैं. गांव के लोगों से उनका संबंध नहीं जुड़ पाता और वे निराश होते हैं. लेकिन बचपन की धुंधलाती स्मृतियों से जुड़ी बेजान चीजों—घर, पगडंडी, श्मशान, मंदिर वगैरह से उनका संबंध जुड़ता जाता है.

इन कहानियों का शिल्प अनगढ़ और सौंदर्य-सृष्टि की दृष्टि से गैर-सर्जनात्मक ही कहा जाएगा. भाषा की आरोपित कृत्रिमता कथा आस्वाद में बाधा पैदा करती है. गैरप्रासंगिक विवरणों का चित्रण लेखक नाहक ही करता है. 'अर्द्धांगिनी' कहानी इसी तरह के विवरणों के चित्रण से भरी है. अन्यथा कहानी-वस्तु के नाम पर उसमें कुछ खास नहीं है. कई बार लेखक अपेक्षित प्रभाव की सृष्टि घटनाओं और पात्रों की मनःस्थितियों से करने में सफल होता है लेकिन लेखक की सीधे कथन की शैली से वह प्रभाव भी नष्ट हो जाता है. एक उदाहरण: "उप्रेती साहब ही बोले, "यहां को चले थे, तब कितनी उमंग थी— अब जान पड़ता है, जैसे किसी ने पांवों की सारी ताकत ही छीन ली हो. जो वस्तु खोजना चाहते थे, यहां शायद कहीं नहीं, गुड्डन की अम्मा! लोगों से पहाड़ की रामलीला के बारे में पूछो तो पंजाब के भिंडरांवाले-लालसिंह-अजैब सिंह का किस्सा शुरू कर देते हैं. पॉलिटिक्स का गू पूरे देश में फैल गया है."

—प्रेम सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोश

गागर में समोया सागर

पर सैकड़ों ग्रंथों से लिए संदर्भों का सतही प्रस्तुतीकरण

प्राचीन भारतीय संस्कृति कोश
डॉ. हरदेव बाहरी
कुल पृष्ठ-1988, कीमत 225 रु.
विद्या प्रकाशन मंदिर,
नई दिल्ली-2

प्राचीन भारतीय संस्कृति पर प्रामाणिकता और दृष्टिगत तार्किकता से चिंतन-मनन प्रस्तुत करने वाले मनीषी विद्वान हिंदी में दिनोदिन कम होते जा रहे हैं. इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस तरह के गहन गंभीर कार्य करने वालों पर न तो कोई अपनी विचार शक्ति खर्च करना चाहता है और न ही इस तरह के कार्य को आदर देने के लिए तैयार होता है. सौ वर्ष के पश्चिमी चिंतन के प्रभाव और शोरगुल से लोगों ने मान लिया है कि भारतीय संस्कृति कोई बात करने लायक विषय नहीं है. आज हालत यह पहुंची है कि 'भारतीयता' और 'संस्कृति' दोनों बहुत ही सताए हुए शब्द हैं और लोग इन दोनों से इसलिए बचते फिरते हैं कि कहीं इनका साथ देने पर अनाधुनिक, परंपरावादी न मान लिए जाएं. ऐसे कठिन समय में डॉ. हरदेव बाहरी ने 'प्राचीन भारतीय संस्कृति कोश' निकालने का साहस (या दुस्साहस) किया है. उन्होंने वैदिक काल से लेकर 12 वीं शताब्दी तक की भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण मिथकों, कथाओं, चरित्रों, अभिप्रायों, लोकमान्य कर्मकांडों और परंपराओं को इस कोश में स्थान दिया है.

डॉ. बाहरी हिंदी कोशकार के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुके हैं. उन्होंने 'वृहत अंग्रेजी-हिंदी कोश', 'प्रसाद साहित्य कोश', 'रूसी-हिंदी शब्द कोश', 'सूरसागर कोश', 'उच्चतर हिंदी शब्द कोश', 'मुहावरा एवं लोकोक्ति कोश' के जरिये हिंदी कोश परंपरा को समृद्ध किया है. उनका ध्यान हिंदी की शब्द-संपदा पर भी केंद्रित रहा है. इस दृष्टि से उन्होंने 'अवधी शब्द-संपदा', 'भोजपुरी शब्द-संपदा' तथा 'छत्तीसगढ़ी शब्द-संपदा' पर वर्षों कार्य किया. हिंदी शब्द-संपदा के संग्रह का कार्य करने के लिए विद्वानों को आगे आना चाहिए इसी मनोभूमिका के साथ वे कोश की ओर गए.

भारतीय संस्कृति की प्राचीनता पर पश्चिमी विद्वानों ने अतार्किक तुकों, गप्पों की शरण ली है. इस दयनीय स्थिति से उबरने के लिए भी डॉ. बाहरी के मन में संघर्ष चलता रहा है. इसी तनावग्रस्त स्थिति में उन्होंने लिखा है कि "तब मुझे लगने लगा कि भारत की वास्तविक संस्कृति सामी जातियों और उनके संप्रदाय के आने के पहले की है. वैदिक काल की संस्कृति हमारी मूल और बहुमूल्य धरोहर है. रामायण काल से लेकर पौराणिक काल तक, विशेषतः गुप्त राजाओं के राज्यकाल में भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े. वैदिक देवता बदल गए, पूजा की नई विधियां आ गईं, केवल विष्णु के ही नहीं, अनेक देवताओं, नागों और राक्षसों तक के अवतार माने जाने लगे." (पृष्ठ 5)

> **"वैदिक काल की संस्कृति हमारी मूल और बहुमूल्य धरोहर है. रामायण काल से लेकर पौराणिक काल तक भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े—देवता बदले, पूजा की नई विधियां आ गईं"**
>
> 'इसी किताब से'

धार्मिक सिद्धांतों के परिवर्तनों ने सांस्कृतिक-सामाजिक चिंतन की चूलों को हिला दिया. साथ ही बाहर से आने वाली जातियां भी अंधड़ की तरह इस देश में आईं. अजीब देश है यह—इसने सभी को अपने में खपा लिया. भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि इसमें विरुद्धों के सामंजस्य की अद्भुत शक्ति है. शक आए, हूण आए, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यूनानी, मंगोल, कुषाण आए और भारत में मिल गए. वैदिक, बौद्ध, जैन, कोल, किरात द्रविड़ सभी संस्कृतियों का जल-प्रवाह मिलकर भारतीय संस्कृति को बनाता रहा है. अतः यह संस्कृति न आध्यात्मिक है न भौतिक. हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध द्रविड़, आर्य, कोल, किरात न जाने कितनी ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं और सभी का रासायनिक घोल से एक संस्कृति बनी जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं. डॉ. बाहरी इस कोश के भीतर इस मेलमिलाप की प्रक्रिया को निरंतर पहचनवाते चलते हैं.

आज जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं वह न जाने कितने आर्य-आर्येतर उपादानों से मिलकर बनी है. एक-एक देवता, एक-एक वृक्ष, एक-एक फूल इसकी मेलमिलाप की कह रहा है. राधा और कृष्ण दोनों अनार्य देवी-देवता हैं, प्रेमी-प्रेमिका हैं लेकिन आर्य संस्कृति में इनके प्रवेश ने प्रेम-प्रवाह सागर प्रवाहित कर दिया है. मेलमिलाप की इस परंपरा को शुद्धतावादी-नस्लवादी भूलते जा रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए भारतीय संस्कृति कोश की गहरी उपयोगिता देयता है. कोशकार ने प्रविष्टियों को सीमा में लिखकर भी अपनी बात स्पष्ट की है. लिखते हैं, "यह कहा जा सकता है कि प्रविष्टियां कुछ अधिक विस्तृत होनी चाहिए थी. यह सही है. प्राचीन भारतीय संस्कृति के पक्ष इतने विशाल हैं, विशेषतः व्यक्ति और स्थानों से संबंधित कथाएं इतनी अधिक हैं, सिद्धांतों की व्याख्या की इतनी गुंजाइश है कि यह कई बड़े-बड़े भागों में लिखा पड़ता. परंतु इस युग का तकाजा कि थोड़े में बहुत कुछ कहा जिससे पाठकों को लाभ हो."

कोशकार की इस बात मानने में आपत्ति इसलिए नहीं चाहिए कि भारतीय संस्कृति प्रस्तुत करनेवाला विशाल साहित्य उपलब्ध है. संस्कृत की पुस्तकों में यह सामग्री भरी पड़ी संतोष की बात है कि कोशकार ने ग्रंथों से इस महत्वपूर्ण सामग्री का किया है. वेद, उपनिषद्, पुराण, रामायण, महाभारत, तंत्रसाहित्य के भीतर से निकाल गई यहां बीस हजार प्रविष्टियां हैं. वाली बात केवल यह है कि डॉ. बाहरी यह कार्य जल्दी में किया है. फलतः वैदुक्य की वह धमक यहां गायब है लिए वे लंबे समय से प्रसिद्ध रहे हैं. तर प्रविष्टियों को सतही ढंग से छूकर दिया गया है. फिर भी यह कोश काफी की चीज है.

—कृष्णदत्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनमोल!

अब, युरेनस II. सबसे आधुनिक डुएल-डेक माइक्रोकम्पोनेंट सिस्टम, जिसमें है डॉल्बी® एन आर.* साथ में बेहतरीन खूबियाँ जैसे हाइ-स्पीड सिंक्रोडबिंग, जिन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय ब्रांडवाले, अधिक महंगे मॉडल्स में ही पाया जाता है.

कॉन्फ़िडेन्स की पेशकश... कुछ गिने चुने लोगों के लिए है आप.

इन्पुट सिलेक्शन के लिए. और है मिक्सिंग की सुविधाएं... माइक्रोफ़ोन इन्पुट के साथ.

आपके कमरे में ध्वनि आवश्यकता के मुताबिक ढालने के लिए ग्राफ़िक इक्वलायज़र. बढ़िया ट्रैकिंग के लिए बड़ी ही सूक्ष्मता से संतुलित किया गया, पट्टी से चलाया जाता टर्नटेबल. देशीय व विदेशी-प्रसारण सेवाओं को सुनने के लिए एएम/एफएम स्टिरीयो मल्टीप्लेक्स ट्युनर और इसका समग्र ३-तरफा ३ स्पीकर वाला सिस्टम-विस्तृत श्रेणी के डोम ट्वीटर के साथ ४०० वॉटस की संगीत शक्ती प्रवाहित करता है.

युरेनस II
ऑडियो इंजीनियरिंग में सुनहरे युग का स्वागत.

युरेनस II-एसडी ५८० केसैट डेक, एसए ५८० स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्प्लीफ़ायर, एसटी ५०० एफएम/एएम ट्युनर, एसक्यू ५०० ग्राफ़िक इक्वलायज़र, एसपी ५०० टर्नटेबल और एसएक्स ९०९ स्पीकर सिस्टम का संपूर्ण नाम ही तो है-युरेनस II.

...ड-स्टॉप और 'सिंको' डबिंग सुविधाएँ. डॉल्बी ...र्केट और निर्दोष रिकॉर्डिंग के लिए ...-मीटिंग व्हीयु मीटर.

...(वीएमपी ओ) की घनघोर बुलंद आवाज देने ...कलर. कोलाहल नियंत्रण और फटती आवाज को ...शेष हाइ फिल्टर. तर्कशुद्ध नियंत्रित स्पर्श स्विचेस

ONODYNE Uranus II

* डॉल्बी ® – डॉल्बी लेबोरेटरीज लायसेंसिंग कॉर्पोरेशन, यु.एस.ए. का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

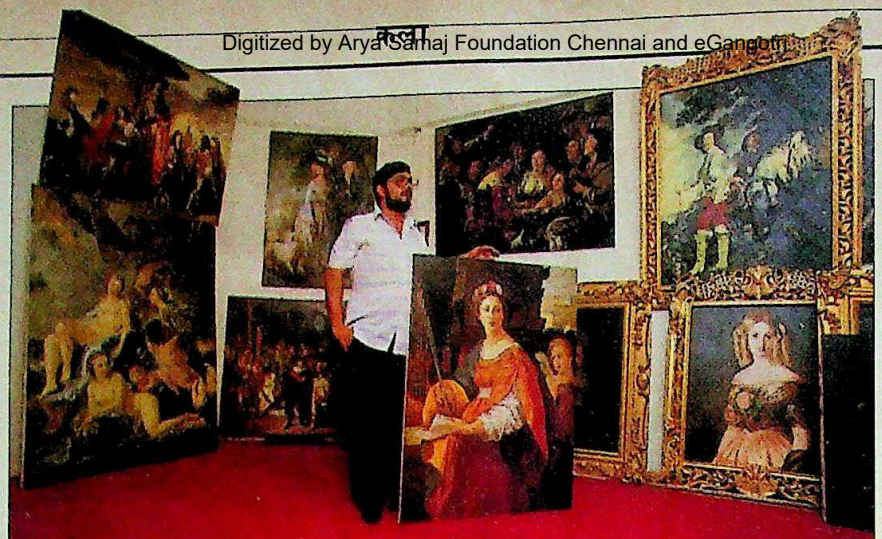

सभी फोटो: नामस भोजानी

असल-सी नकल

दक्षिण बंबई की एक छोटी-सी गली में निचले तल्ले पर वास्तुशिल्पी जहांगीर पी. वजीफदार के कार्यालय की दीवारें यूरोपीय चित्रकला के महान चितेरों—लियोनार्दो द विंची से लेकर इंग्रेस तक की कुछ शानदार कृतियों के नमूनों से अटी पड़ी हैं. लेकिन ये केवल कलाकृतियों की नकल भर हैं जो भारत में असली कलाकृतियों की बढ़ती मांग से मुनाफा कमाने के धंधे में काम आती हैं.

वजीफदार और उनके वास्तुशिल्पी बेटे फीरोज ने छह महीने पहले द विंची, कोरेगिओ, ड्यरर, रेब्रां, रूबेंस, बोटीसेल्ली, टिटियन, रैफैल, गोया सरीखे यूरोपीय संग्रहालयों में ही दिखाई देने वाले जाने-माने चित्रकारों की कलाकृतियों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए 'स्टुडियो विंडसर' नाम से एक कंपनी बना डाली. जल्द ही ये पुरानी उत्कृष्ट कलाकृतियों की प्रतिलिपियां उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा दिलाने का साधन बन जाएंगी इन कलाकृतियों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए तकरीबन 50 कलाकार उनके पास जुट आए. इन चित्रों पर अंतिम ब्रुश चित्रकार जहांगीर वजीफदार ही चलाते हैं.

कुछ ही महीनों में वजीफदार के पास पुनर्जागरण काल और शास्त्रीय स्वरूप की कलाकृतियों का भारी जखीरा इकट्ठा हो गया. वजीफदार ने इनमें से हरेक के दाम 15,000 रु. या उससे ऊपर निर्धारित किए. स्टुडियो विंडसर इनमें से कई कृतियों की बिक्री कर चुका है. उनके ग्राहकों में व्यापारी तो हैं ही, पांच सितारा होटलों की तरह की कंपनियां भी हैं. फीरोज

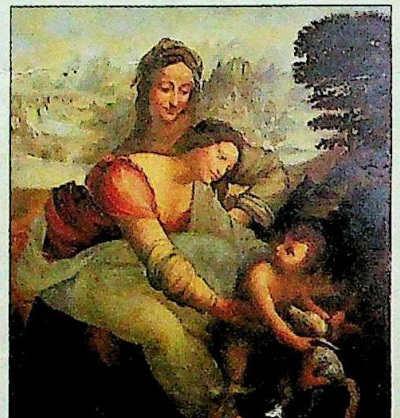

वजीफदार कहते हैं, "हमें उम्मीद है कि भारत में यूरोपीय शास्त्रीय कला के प्रति लोगों की दिलचस्पी फिर से जगाने में स्टुडियो विंडसर कुछ तो हाथ बंटा सकेगा."

वजीफदार ने जिन चित्रकारों को काम पर लगाया उन्हें शुरू में लगा कि इन विदेशी कलाकृतियों की प्रतिलिपियां तैयार करना मुश्किल है क्योंकि उनके रंग धुंधला गए हैं और आकृतियों की भावभंगिमाएं एकदम अस्पष्ट हैं. ऐसे में जो प्रतिकृतियां निर्धारित स्तर की नहीं बन पाईं उन्हें रद्द कर दिया गया. ऐसी तकरीबन 50 कलाकृतियां विंडसर स्टुडियो के पिछले कमरे में पड़ी हुई हैं. बाकी प्रतिकृतियां दुबारा कलाकारों को सौंपी गईं. जहांगीर वजीफदार ने उन्हें बताया कि उनका स्तर कैसे सुधारा जा सकता है. विंडसर स्टुडियों ने जिन मशहूर कलाकृतियों की नकल तैयार

(ऊपर बाएं) फीरोज अपने स्टुडियो में
और प्रख्यात चित्रों की प्रतिलिपियां
अक्ल से नकल

करने की योजना बनाई है उनमें विंची
'मोनालीसा' शामिल नहीं है. फीरोज क
हैं, "यह बेहद प्रसिद्ध है और हम इन
प्रतिकृति जरूर तैयार करेंगे. लेकिन
काम को अंजाम देने के लिए हम
कलाकार की तलाश कर रहे हैं. हमने
किया है कि किसी भी कलाकृति की एक
ज्यादा प्रतिलिपि तैयार नहीं की जाए.

पश्चिमी देशों में तो ऐसी प्रतिलि
मूल चित्रों को देखकर तैयार की जा
लेकिन विंडसर स्टुडियो के चित्रकारों
छपे हुए उन चित्रों से प्रतिलिपियां
करनी पड़ती है, जिनमें से मूल चित्र
और बारीकियां दोनों लगभग गायब
हैं. इसके बावजूद कई प्रतिकृतियों में
चित्र की खूबियां नजर आती हैं. इस
विंडसर स्टुडियो महान कलाकारों
कृतियों की प्रतिलिपि तैयार करने की
परंपरा को पुनः प्रचलन में ला र
जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में
चित्रकार जे. पीठावाला सरीखे लोगों
थी. चेमोल्ड गैलरी के केको गांधी क
"मुझे लगता है कि स्टुडियो विंडस
प्रतिकृतियों को बाजार मिल जाएगा
इनके खरीदार समकालीन कला
रखने वालों से भिन्न होंगे."

जाहिर है विंडसर स्टुडियो की
कृतियां उन्हीं इमारतों में लग सकती
का आंतरिक परिदृश्य यूरोपीय
वाला हो.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

कुछ होते . . . मौज मस्ती करते बच्चों को देखना आपको ख़ुश करने के लिए काफ़ी है. बच्चों के लिए जितने ज़रूरी हैं खाना-पीना और हवा उतनी ही ज़रूरी है हंसी-ख़ुशी . . . मौज-मस्ती. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती . . . यही मज़े. एकदम वैसी ही कॉमिक पत्रिका जो हर बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है. आख़िर डिस्नी गैंग के सदस्य दुनिया भर के आधे बच्चों के चहेते हैं . . . मनपसंद हैं.

तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को ख़ुश कर दीजिए.

यही है अद्भुत तरीका बच्चों को यह जताने का कि वे आपकी ज़िंदगी में हमेशा-सदा सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे. सबसे बढ़िया बात यह कि घर भर में गूंज उठे आपकी चहेती आवाज़.

आपके बच्चे की खिलखिलाहट.

आज ही सबस्क्रिपशन भेजिए और आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कृपया निम्नलिखित पते पर भेजें :
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि०
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
रूपायन प्रेस बिल्डिंग
प्लॉट नं. 69 दिल्ली-मथुरा रोड
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा
☐ सालाना: रु. 78/- ☐ छह महीने का: रु. 40/- हिन्दी
प्रति के लिए सबस्क्रिपशन. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट
नं _____ द्वारा कर रहा हूँ.
कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय: _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

114

DISNEY COMICS

डिस्नी टुडे

अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिंदी और अंग्रेज़ी में.

© THE WALT DISNEY CO., USA.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तैयब बादशाह

◆ सदाबहार देवानंद युवा और हसीन चेहरों की सोहबत पसंद करते हैं. इन्हीं चेहरों में एक है 18वें वर्ष में कदम रखती सुंदर, शर्मीली **एकता** यानी आरती शर्मा का. अपनी इस नई खोज को देवानंद ने ही नया नाम दिया है. फिल्म 'अव्वल नंबर' में वह ऐसी नायिका की भूमिका कर रही है जिसके मन के तार दो क्रिकेट खिलाड़ियों से जुड़ जाते हैं. अंततः उसे एक को चुनना पड़ता है. देवानंद तो एकता को मासूम बताते हैं पर वह कहती है, "देव साहब ने मुझसे पहले जिन हीरोइनों को खोज निकाला था उन सबसे मैं बेहतर काम कर दिखाऊंगी."

एकताः सदाबहार खोज

◆ मशहूर व्यंग्यचित्रकार **आर.के. लक्ष्मण** के व्यंग्यचित्रों का कुर्ता-धोतीधारी आम आदमी अब टीवी पर पदार्पण करने जा रहा है. सीरियल 'वागले की दुनिया' में उसकी व्यथाकथा देखी जा सकेगी. इसमें वागले को हमेशा से सताए गए एक मध्यमवर्गीय आदमी के रूप में पेश किया गया है.

रघु राय

इस धारावाहिक को लक्ष्मण ने व्यंग्य की अपनी विधा के अनुरूप ढालने की विलक्षण कोशिश की है. मैगासाय-साय पुरस्कार विजेता व्यंग्यकार कहते हैं, "मैंने इसमें हास्य का पुट कम किया है और कटाक्षों पर जोर दिया है." बहरहाल, लचर धारावाहिकों से ऊबे टीवी दर्शक उनसे चुटकियों से सराबोर मनो-रंजन की उम्मीद कर सकते हैं.

◆ एअर इंडिया के महाराजा इसी महीने पहली महिला पायलट की अगवानी करेंगे. ये हैं **हरप्रीत अहलुवालिया** जो इस वर्ष 22 वर्ष की हो जाएंगी. व्यावसायिक उड़ानों के लिए पायलट का लाइसेंस मिलने के बाद जब एअर इंडिया ने उन्हें चुना तो वे मानो सातवें आसमान पर ही पहुंच गईं. वैसे भी आसमान की ऊंचाई नापना उनके लिए कोई नई बात नहीं है. उनके पिता भारतीय वायुसेना के अधिकारी रह चुके हैं. हरप्रीत कहती हैं, "मैं कुछ अलग ही कर दिखाना चाहती थी." उन्हें प्रधानमंत्री राहत कोष से 45,000 रु. का वजीफा मिल गया था. यानी राजीव के होते हुए पायलट बनने के सपने संजोने वालों के लिए मंजिल आसान रहेगी.

हरप्रीतः सातवें आसमान पर

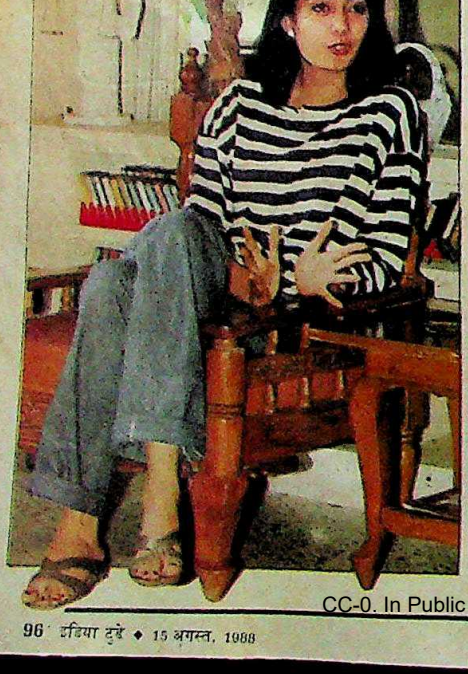

◆ पेचीदा प्रश्न है. अमेरिका में बसे भारतीय हर साल जिस सर्वश्रेष्ठ भारतीय सुंदरी का चुनाव करते हैं उसे क्या कहा जाए—मिस इंडिया (अमेरिकी) या (अमेरिकी) मिस इंडिया. जो भी चाहे कह लें पिछले पखवाड़े न्यूयॉर्क के शेराटन होटल में इस सम्मान का सेहरा 19 वर्षीया **वैशाली माथुर** के सिर बंधा. टेक्सास में रहने वाली 5 फुट 5 इंच की इस सुंदरी को अपनी प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए कथक नृत्य का जोरदार प्रदर्शन करना पड़ा. प्री-मेडिकल की छात्रा वैशाली कहती है, "फिल्मों में जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है." उनके बयान में गौर करने वाला शब्द है 'फिलहाल'.

वैशालीः नृत्य का पुरस्कार

नासस भोजानी

'वागले की दुनिया' का एक और (ऊपर) लक्ष्मण

◆ और अब चार्ली चैपलिन भारत में—कभी कश्मीर में चहलकदमी करते तो कभी वादियों को दबोचते और [illegible] बातचीत करते. चैपलिन [illegible] तीय अवतार बनेंगे 'हम लल्लू यानी **राजेश पुरी**. यह वे वीडियो फिल्मों की सिरी लिन चैपलिन' में निभाए ब्लॉसम पॉलिश के बहुचर्चि पन में भी पुरी चैपलिन [illegible] वे कहते हैं, "बचपन से ही मेरे सपनों के सरताज [illegible] पास उनकी लगभग सभी फिल्मों के वीडियो रिक्ा के दिनों से ही मैं मं की भूमिका निभा सिरीज की पहली फि इन कब्रिस्तान' में स्तान में नजर आएंगे

पुरीः चैपलिन बने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, [illegible]

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

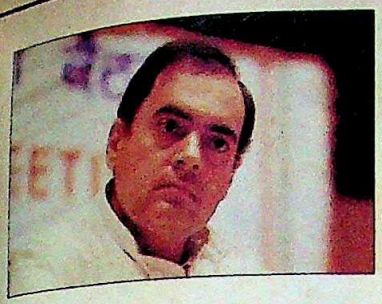

फीकी पड़ गई चमक-दमक

कई तरह के घोटालों, अंदरूनी असंतोष और उपचुनावों में मिली पराजय की वजह से मतदाताओं पर इंका की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है. इंका ने कितना कुछ गंवाया है इसका लेखा-जोखा 'इंडिया टुडे' द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए जनमत संग्रह में.

आवरण कथा.....14

बंधी मुट्ठी लाख की

विपक्षी एकता के नाटक का दूसरा अंक पिछले पखवाड़े दिल्ली में खेला गया. नंदमूरि तारक रामराव ने सात विपक्षी दलों को इंका के खिलाफ एक होकर राष्ट्रीय मोर्चा गठित करने को मजबूर कर दिया. परदे के पीछे चली जोड़-तोड़ का विश्लेषण.

आजकल.....26

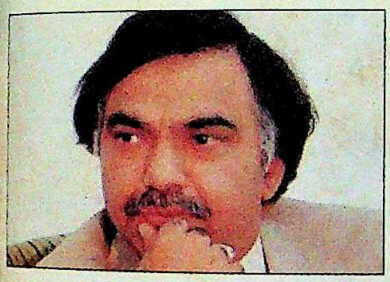

पहुंच के बूते पौ-बारह

प्रधानमंत्री की मित्रमंडली के एक और सदस्य अचानक करोड़ों के घोटाले के फेर में फंस गए हैं. दिल्ली के व्यापारी ललित सूरी ने जापान की एक कंपनी को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से ठेका दिलवाने में मदद की. मामले की पड़ताल.

खास रपट.....42

सितारा फिर दमकने लगा

लंबे अरसे की मंदी के बाद रिलायंस उद्योग का सितारा सरकार की उदार नीतियों का सहारा पाकर एक बार फिर बुलंदी पर है. इस पखवाड़े उसने एक नई पेट्रोरसायन कंपनी खोलने का निर्णय करके मानो विवादों का पिटारा खोल दिया है.

कारोबार.....64

जीते हैं शान से

बरसात के साथ ही मनुष्य की नाक में दम कर देने वाला जीव मच्छर लौट आया है. मारक दवाओं से बेअसर, दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाला यह कीट दिन-दूनी-रात-चौगुनी रफ्तार से फल-फूल रहा है. आकार में छोटे इस खतरनाक जीव पर एक पैनी नजर.

विशेष लेख.....74

सच होता सपना

भारत के वैज्ञानिक ऐसे हल्के लड़ाकू विमान तैयार करने की परियोजना में तेजी से जुटे हैं, जो 1995 में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन सकेंगे. लेकिन इसमें उन्हें कड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है. परियोजना की प्रगति पर एक तथ्यपरक रिपोर्ट.

प्रतिरक्षा.....78

अगले पन्नों पर

कसौटी.....8
राजरंग.....9
तेवर.....10
हिंदोस्तां हमारा.....11
बीता पखवाड़ा.....12
आवरण कथा
राजीव गांधी: फीकी पड़ गई चमक-दमक.14
आजकल
कर्नाटक: मूल्यों की महंगी कीमत.....24
विपक्ष: बंधी मुट्ठी लाख की.....26
दिल्ली: बेमतलब कुर्बानियां.....28
प. बंगाल: मारक मिलावट.....30
पंजाब: बेतुकी कार्रवाई.....32
नगालैंड: लोकतांत्रिक प्रक्रिया ताक पर.....33
सैयद मोदी: रहस्यमय हत्या.....35
बिहार: असंतोष की अनबुझी आग.....37
बात पते की.....38
गुजरात: रास हाथ में.....39
लद्दाख: अनोखा उपहार.....40
केरल: अपवित्र पापी.....41
खास रपट
ललित सूरी: पहुंच के बूते पौ-बारह.....42
राज्य-दर्पण.....46
खास रपट
तमिलनाडु: तुरुप के पत्ते की चाल.....48
पड़ताल
मध्य प्रदेश: तबादले का 'धंधा' फिर गरम.52
विधि-विधान
इंदिरा हत्याकांड: अहम मुकदमा.....55
पास-पड़ोस
अफगानिस्तान:
भावी मुसीबतों के संकेत.....56
पाकिस्तान:
सिखों को सिर्फ सरकारी शह.....60
व्यापार चक्र.....63
कारोबार
रिलायंस: सितारा फिर दमकने लगा.....64
उद्योग: नई राह, नई मंजिलें.....66
स्कूटर: अपने-अपने दावे.....69
भविष्य निधि: हक पर हमला.....70
टेल्को: पहियों की तेजी.....71
शेयर बाजार.....72
अपराध
दिल्ली: रक्त से सना हुआ प्रेम.....73
विशेष लेख
मच्छर: जीते हैं शान से, मारते हैं जान से..74
प्रतिरक्षा
हल्के लड़ाकू विमान: सच होता सपना.....78
पर्यटन
गोवा: काली घटाओं का बुलावा.....85
खेलकूद
हॉकी: पुराने दिग्गजों की नींद टूटी.....86
समाचार माध्यम
के भाग्यराज: भविष्य उज्ज्वल.....88
टीवी
'उल्टा-पुल्टा': सीधी बातें टेढ़े तरीके से.....89
रामायण: मांग पर होगी वापसी.....90
किताबें.....91
चर्चित चेहरे.....96

आवरण फोटो: प्रमोद पुष्करणा
रूपरेखा: अनूप गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहली नज़र में फ़िदा.

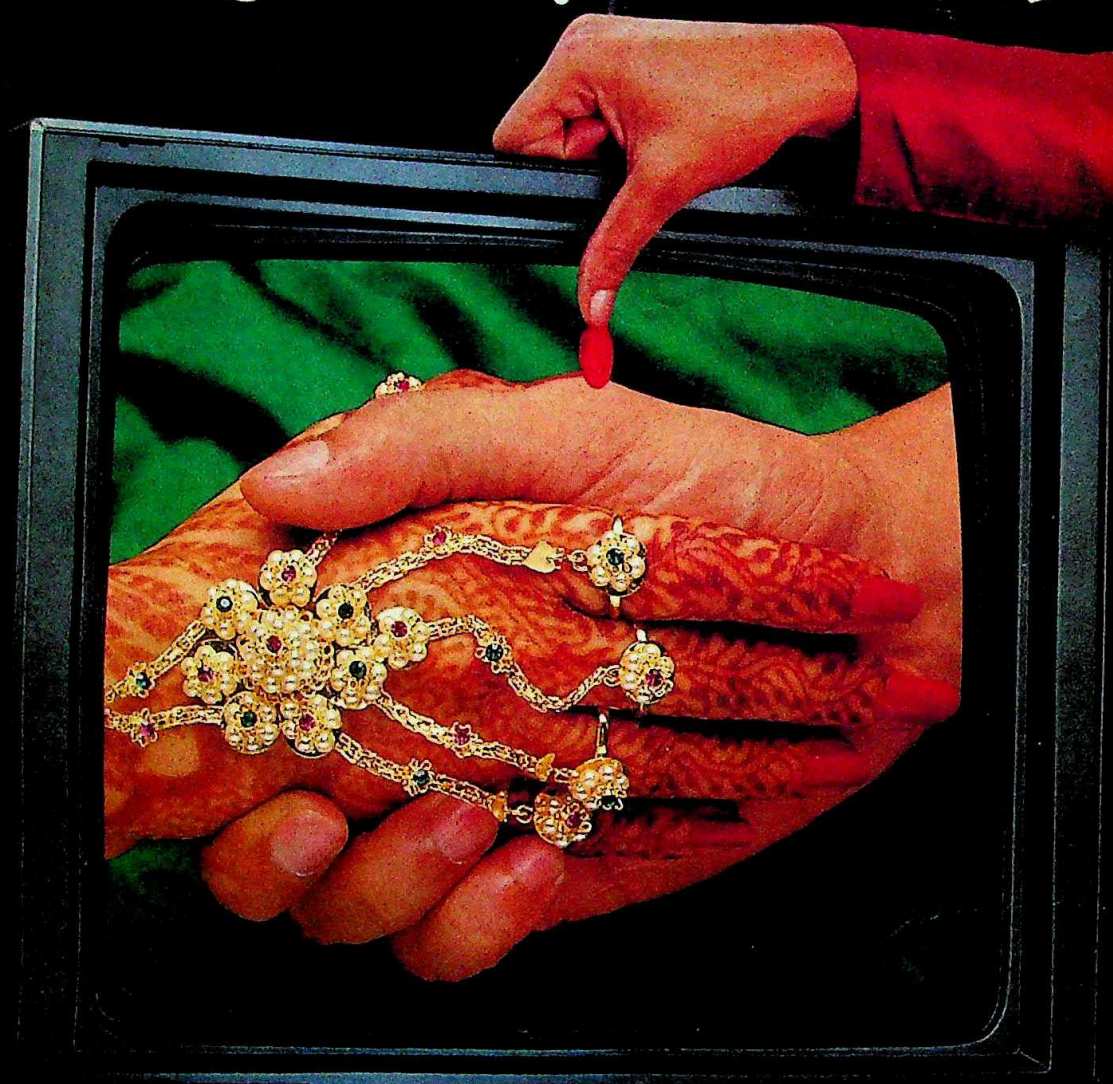

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भारत में निर्माता : कल्याणी शार्प इंडिया लि.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बस, नज़र पड़ते ही आप जी-ज़ान से न्यौछावर... यही तो है ऑप्टॉनिका का करिश्मा... जीवन भर के लिए... ऑप्टॉनिका, एकमात्र टीवी, जो आपकी नज़रों के सामने **ट्रू-लाइफ़ विज़न** का ख़ज़ाना खोलने को तैयार है.

पुस्तकालय
गु० कां० विश्वविद्यालय

ट्रू-लाइफ़ विज़न – सच्चाई का दर्पण... तराशी तस्वीरें... स्पष्ट और तीखी... **हाइ सेन्सिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर** की बदौलत, **कलर डिकोडर सर्किट** के कारण नैचुरल रंगों का स्वाभाविक दर्शन, **ऑटो लिनियरिटी कंट्रोल** की वजह से सही आकार... सही स्वरूप. **ऑप्टिमैटिक पिक्चर कंट्रोल** याने कॉन्ट्रास्ट का खुद-ब-खुद फिर से ठीक और व्यवस्थित हो जाना.

ऑप्टॉनिका – सुंदर, भरोसेमंद – जीवन भर के साथ का वायदा लिए...
ऑप्टॉनिका – पहली नज़र में ही आप इसके हो जाएंगे!

OPTONICA

ट्रू-लाइफ़ विज़न... ज़िंदगी भर के लिए!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

HILLIDAY

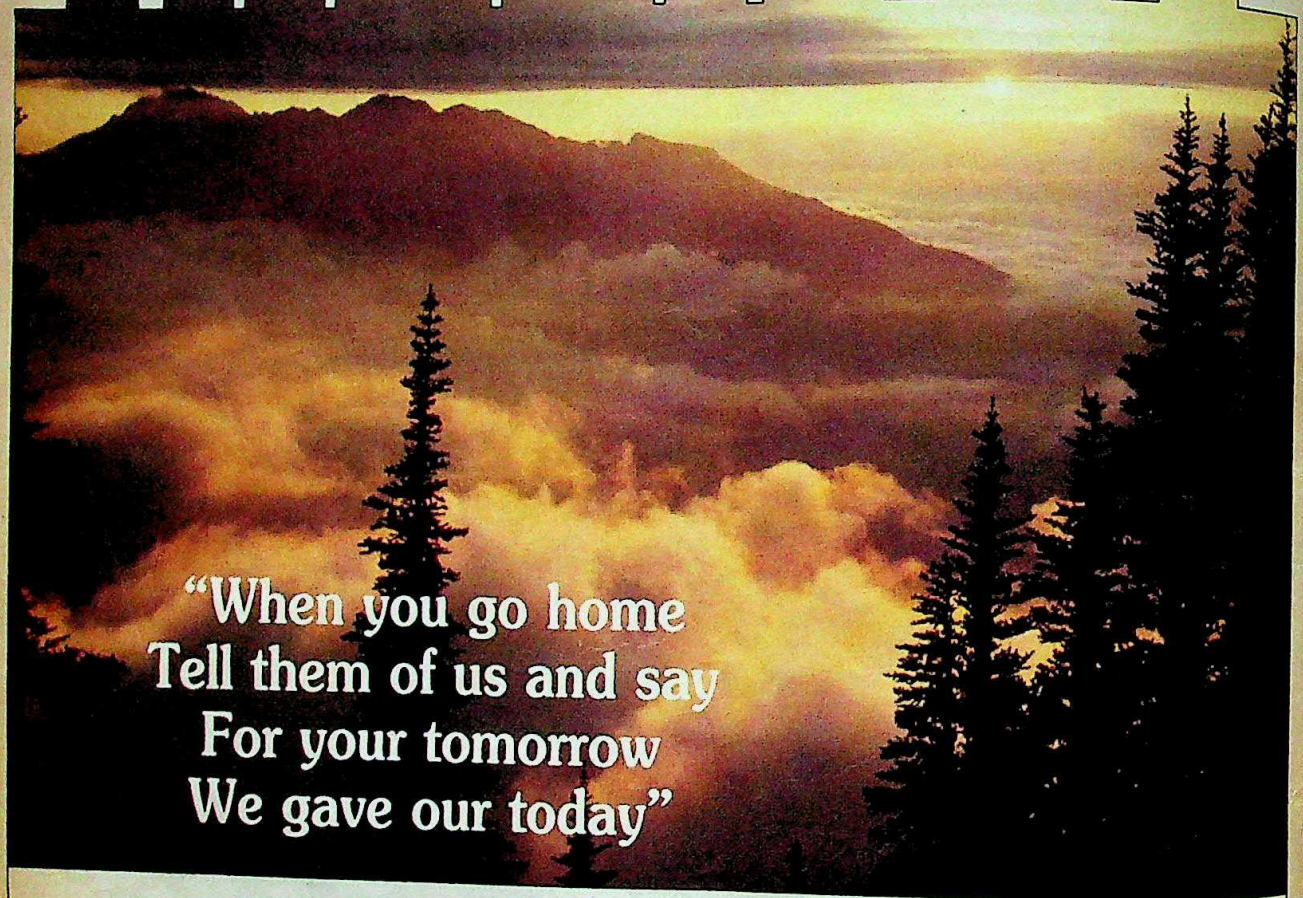

''घर जाकर उन्हें
हमारे बारे में बतलाएँ
आपके कल के लिए
हमने अपने प्राण लुटाए''

ये भावपूर्ण शब्द कोहिमा में शहीदों के स्मारक स्थल पर लगी कांस्य पट्टिका पर अंकित हैं. उन वीरों के साहस, धैर्य और क्षमता का शाश्वत बयान जिन्होंने 1944 में भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये. एक मार्मिक अनुभव.

नगालैण्ड. शान्त. प्रकृति का नैसर्गिक स्वरूप आकर्षक आर्किड्स. नीली-नीली पर्वत चोटियों का ऐसा मोहक रूप जो मन-प्राण में भर दे ताज़गी का अनूठा अहसास.

कोहिमा से थोड़ी ही दूरी पर है इम्फाल, मणिपुर. हरी भरी नदी घाटियाँ. रंगीले, खुशमिज़ाज लोग. शानदार मणिपुरी नृत्य. विभिन्न रंगों की दिलकश झलक लिए आर्किड्स की 500 किस्में. लोकटक झील में छोटे-छोटे टापुओं पर बनी सुविधाजनक हट्स.

और गंगतोक, सिक्किम, तो ज़रूर ही जाइए. एक यादगार अनुभव रहेगा. मुस्कुराते, स्नेह और अपनेपन की भावना से भरे पूरे लोग. एक नई सी दुनिया. शिखरों पर स्थित बौद्ध मठों की गरिमा और कंचनजंगा की मनोहारी छटा निश्चित ही आपका मन मोह लेगी.

'हिलिडे' पर आइए. पूर्वोत्तर पहाड़ियों के जादू में खो जाइए.

वहाँ पहुँचें कैसे :

	विमान द्वारा (निकटतम हवाई अड्डा)	रेल द्वारा (निकटतम रेल्वे स्टेशन)
कोहिमा	दीमापुर	दीमापुर
इम्फाल	गुवाहाटी/सिलचर	दीमापुर
गंगतोक	बागडोगरा	सिलीगुड़ी

- **सबसे बढ़िया मौसम :** अक्टूबर से फ़रवरी
- **कपड़े :** ऊनी
- और अधिक जानकारी केलिए अपने ट्रैवल एजेंट या संबंधित राज्यों के पर्यटन विभागों से संपर्क करें.

कोहिमा. इम्फाल. गंगतोक.
क्योंकि ज़िन्दगी मे कुछ यादगारें होनी हीं चाहिए.

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 2, अंक: 20, 16-31 अगस्त 1988

प्रधान संपादक
अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक
प्रभु चावला

संपादकीय विभाग
जगदीश उपासने, अशोक कुमार
विजय क्रांति, ओम प्रकाश सराफ
अरविंद मोहन मिश्र

प्रोडक्शन
अनिल शर्मा, सुबाचन यादव
सुनील सैनी

■ **संपादकीय कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली.

■ **मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:** इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

■ **मुख्य विज्ञापन कार्यालय:** 28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया, बंबई.

■ **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली • फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास • 74/1 सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर • 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता. • कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता. • लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

नेपाल में 6 रुपए

उम्मीदें पूरी करें

विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर आवरण कथा 'हो गया गठजोड़, मगर कितनी पक्की डोर' (15 अगस्त) में आपने सामयिक मुद्दा उठाया है. आज सत्ता दल की तानाशाही और निठल्लेपन से परेशान देश का हर जागरूक नागरिक बड़ी आशा से इन नेताओं की ओर देख रहा है. ऐसा नहीं है कि विपक्षी नेता सशक्त विपक्ष की उपयोगिता से अनजान हैं. वे जानते हैं कि कांग्रेस विपक्ष से कम मत पाकर भी सत्ता हासिल करती रही है. पर वे अपने तुच्छ स्वार्थों के हाथों मजबूर हैं. पल-पल बदलती नीति और आपसी द्वेष से वे देश में लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला कर रहे हैं.

—गुरमीत सिंह सलूजा, कानपुर (उ.प्र.)

■ सशक्त विपक्ष के अभाव में लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है. यदि विपक्षी नेता अब भी पदलोलुपता, दलीय वर्चस्व या अस्तित्व के खतरे वाली मानसिकता और सैद्धांतिक मतभेदों को भुलाए बिना एकता का दिखावा करते हैं तो 1977 की भांति आम जनता के साथ वे खिलवाड़ ही करेंगे.

—सुभाष सेंगर 'पार्थिव', भोपाल (म.प्र.)

■ सच तो यह है कि आपसी घृणा से ऊपर उठकर विपक्षी नेता यदि एकमत होने के अपने संकल्प को क्रियान्वित कर दें तो 'कितनी पक्की डोर' का सवाल ही खत्म हो जाएगा. आंकड़े सबूत हैं कि विपक्षी दलों को अलग-अलग मिलने वाले वोट जब एक जगह जुट जाएं तो इंका की हार को कोई नहीं टाल सकता. हां, विपक्षी नेताओं को इस बारे में जनता को आश्वस्त करना होगा कि वे 1977 की भूल नहीं दोहराएंगे.

—अजय सायुर, सुजानगढ़ (राज.)

■ आवरण कथा बेहद सटीक और तथ्यपरक लगी. राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन भारत में कभी भी संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि विपक्ष का हर नेता तो खुद को प्रधानमंत्री पद का सही हकदार ही समझता है. चुनावी तालमेल भी ये लोग ठीक से नहीं निभा पाते क्योंकि हर विपक्षी घटक अपने-अपने उम्मीदवार की सिफारिश करता है. और सारे प्रयासों का नतीजा वही ढाक के तीन पात ही रहता है.

—डॉ. पुष्पेंद्र कुमार वशिष्ठ, बदायूं (उ.प्र.)

■ विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त विपक्ष का निर्माण एक सराहनीय प्रयास है. विपक्ष के विभिन्न दलों में बंटे रहने के कारण ही कांग्रेस इतने सालों से बहुमत में रहती आई है. जबकि इंका से जनता का विश्वास उठ चुका है, विपक्षी दलों की एकता देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है.

—राजीव रंजन केसरी, आरा (बिहार)

भारतीय नीरो

हर बार की तरह इस बार भी कसौटी 'पर्यटन प्रेम बनाम घरेलू सच' (15 अगस्त) खरी व सटीक लगी. इन निरर्थक दौरों से राजीव की छवि देश की समस्याओं से लापरवाह, गरीब जनता के धन पर मौजमस्ती करने वाले नेता की बनती जा रही है. देश की मौजूदा हालत को देखते हुए राजीव गांधी की तुलना रोम के बादशाह नीरो से करना बहुत ही सटीक लगा.

—संजय दीक्षित, ललितपुर (उ.प्र.)

निष्क्रियता का नतीजा

'रक्तबीज अभी जिंदा है' (15 अगस्त) पढ़ा. एक सुक्खा सिपाही के मारे जाने से आतंकवाद के हाथ पंगु नहीं हो सकते. दरअसल ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तुरंत बाद सरकार अगर व्यापक पैमाने पर आतंकवादियों के खिलाफ ईमानदारी से जेहाद छेड़ देती तो आज स्थिति दूसरी होती. पर केंद्र सरकार चुनावी लाभ के लिए पंजाब समस्या को अगले आम चुनाव तक लटकाए रखना चाहती है. उसे केवल कुर्सी दिखाई देती है. हजारों बेगुनाह, मजलूम लोगों की चीख-पुकार उसे सुनाई नहीं पड़ती.

—एस. राजाशेखरन, नई दिल्ली

अफसोसनाक

'लापरवाही का कहर' (15 अगस्त) बहुत ही हृदय विदारक लगा. देश की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजधानी में सरकार की नाक के नीचे नागरिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का यह हाल है तो बाकी जगह का भगवान ही मालिक. दुख की बात यह है कि नागरिकों की इन बुनियादी जरूरतों की ओर भी सरकार का ध्यान तभी जाता है जब उसे वोटों की जरूरत होती है.

—भारती गुप्ता, लखनऊ (उ.प्र.)

सख्त उपाय जरूरी

भारत में पुलिस को अनुशासित संगठन का दर्जा मिला हुआ है. इसलिए 24 जुलाई को गुजरात में हुआ पुलिस विद्रोह 'होश में लाने का टेढ़ा उपाय' (15 अगस्त) निस्संदेह चौंकाने वाला था. एक सशस्त्र संगठन, जिस पर जनता के जान-माल और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यदि खुद ही आगजनी और पथराव पर उतर आए तो यह प्रशासन की समूची सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्नचिन्ह है. बाकी राज्यों की पुलिस भी बगावत पर न उतर आए, इसके लिए और टेढ़े उपायों का प्रावधान होना ही चाहिए.

—आलोक कुमार झा, भागलपुर (बिहार)

उत्साह बढ़ाया

आवरण कथा 'कदमों के नए निशां...' (31 जुलाई) ने बहुत प्रभावित किया. लेख पढ़ कर लगा कि अपने पसंदीदा काम को व्यवसाय बनाकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के साथ-साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है. इस अंक ने उन महिलाओं को जरूर एक नई राह दिखाई होगी जो कुछ करना चाहती हैं, मगर असमंजस में कुछ कर नहीं पातीं.

—चंद्रा अवस्थी, जबलपुर (म.प्र.)

■ यह लेख छापकर आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है क्योंकि ऐसे लेख पढ़कर हममें भी कुछ कर गुजरने की उमंग जागने लगती है. इन महिलाओं के संघर्षों से यह स्पष्ट है कि यदि कुछ नया कर दिखाने का सपना और दृढ़संकल्प हो तो व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता.

—उमा चौहान, मारवाड़ (राज.)

■ लेख बहुत प्रेरणादायक था. अब सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि निजी व्यवसाय में भी, जिसमें आने से वे अब तक हिचकती रही हैं, महिलाएं तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं. यह इस बात का सबूत है कि आज महिलाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए कितनी प्रत्यनशील हैं.

—शकुलता डूंगरवाल, कोटा (राज.)

■ आपने उन महिलाओं की सफलता का राज बताया है जिन्होंने हजारों-लाखों रुपयों की पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया था और आज लाखों-करोड़ों कमा रही हैं. ये सभी महिलाएं उच्चशिक्षित और संपन्न घरानों से हैं जिनके पास आगे बढ़ने के साधन थे. किसी निम्न वर्ग की जुझारू महिला की सफलता का भी उल्लेख किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता.

—विनय सौरभ, नोनीहाट (बिहार)

■ लेख पक्षपातपूर्ण लगा. आपने उन्हीं महिलाओं को चुना है जो संपन्न घरानों से हैं, जिन्हें न तो पूंजी जुटाने में दिक्कत आती है न अनुदान, कर्ज आदि लेने में. पति या पिता का सहारा भी उन्हें मिलता रहता है. कृपया उन महिलाओं के बारे में भी जानकारी दें जो गरीब और साधन रहित होते हुए आगे बढ़ी हों.

—दीपक कुमार, कलकत्ता (प. बंगाल)

बड़ों पर अंकुश जरूरी

कसौटी के अंतर्गत 'चक्के की चुनौतियां' (31 जुलाई) पढ़ी. राजीव सरकार ने आर्थिक विकास का जो मार्ग अपनाया है उससे लगता है कि भारत पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. लाइसेंस नीति में छूट के कारण उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों की ओर आकृष्ट होंगे और इन क्षेत्रों का भी समुचित विकास हो पाएगा. लेकिन यदि सरकार अर्थव्यवस्था में सचमुच में बदलाव लाना चाहती है तो उसे बड़े उद्योगपतियों पर अंकुश लगाकर छोटे और नए उद्यमियों को पनपने का मौका देना चाहिए.

—आभा उपाध्याय, भोपाल (म.प्र.)

पाठकों से

छपाई की कुल लागत, खासकर अखबारी कागज की कीमत बढ़ जाने के कारण हमें 15 सितंबर 1988 के अंक से 'इंडिया टुडे' की कीमत मजबूरन 5 रुपए से बढ़ा कर 6 रुपए करनी पड़ रही है. लेकिन वार्षिक ग्राहकों के लिए चंदा पहले की तरह 120 रु. ही रहेगा.

स्वार्थी राजनीति

कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े पर आए राजनैतिक संकट 'भारी पड़ता भितरघात' (31 जुलाई) ने यह साबित कर दिया है कि आज राजनीति कितनी क्षुद्र और स्वार्थी हो गई है. दो साल पहले हेगड़े में अगाध विश्वास करने वाले उनके साथी सत्तालोलुपता के कारण उनके दुश्मन हो गए. हेगड़े ही नहीं, देश के उच्च पदस्थ नेता को भी अपने सहयोगियों का सहयोग हासिल करने के लिए उन्हें कोई न कोई पद देना पड़ता है.

—नरेंद्र जैन, देवास (म.प्र.)

चिंतनीय खबर

'समाज को सलीब का सहारा' (31 जुलाई) में ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का समाचार चिंतनीय है. वैसे किसी आदिवासी द्वारा ईसाई धर्म को स्वीकार करना अनुचित नहीं है लेकिन विदेशी मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर, बहकाकर ईसाई बनाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करना खतरनाक है. अरुणाचल सरकार को चाहिए कि 1978 के धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्ती से लागू करे और पड़ोसी राज्यों के सहयोग से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को रोके.

—शकुनचंद, रायबरेली (उ.प्र.)

■ रिपोर्ट बहुत सटीक और निष्पक्ष लगी. खास बात यह लगी कि आपने विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं का गंभीरता से विवेचन किया है, जबकि ज्यादातर लेख आलोचना से भरे होते हैं. आश्चर्य इसी बात का है कि केंद्र और राज्य सरकारें इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं.

—आलोक जैन, भीलवाड़ा (राज.)

संयम जरूरी

'दहशत की दस्तक' (31 जुलाई) में यह पढ़कर आघात-सा लगा कि भारत में भी 332 लोग पश्चिम के इस भयावह एड्स रोग की गिरफ्त में आ चुके हैं. आज जरूरत इस बात की है कि लोग जीवन में संयम को स्थान दें. भारत में जहां मामूली बीमारियों का इलाज भी सहज सुलभ नहीं, भोग संस्कृति पर पाबंदी लगाकर ही इस रोग से बचा जा सकता है.

—श्याम मनोहर, उदयपुर (राज.)

■ भारत में एड्स के 332 रोगियों का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाया जाना निश्चय ही बड़े खतरे की घंटी है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए. सरकार को चाहिए कि रेडियो, टी.वी. आदि के माध्यम से इस रोग से संबंधित जानकारी आम जनता तक पहुंचाए.

—अश्विनी सैनी, मोदी नगर (उ.प्र.)

जमीन दे देते

'शहरी चकाचौंध का दुष्चक्र' (31 जुलाई) पढ़कर लगा कि सरकार ने हवाई अड्डे के विकास के लिए ली गई जमीन के बदले गांव के लोगों को नोटों की बरसात न करके खेती व आवास के लिए कहीं जमीन दे दी होती तो ये दुष्परिणाम सामने न आते.

—पी.एस. कुकरेती, देहरादून (उ.प्र.)

मुख्यमंत्री यही करेंगे?

यह जानकर अफसोस होता है कि जिन नेताओं के हाथ में जनता देश की बागडोर सौंपती है उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है विपक्ष को खत्म करना. 'बदलाव तो होना ही था' (31 जुलाई) में शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका के बारे में बताते हैं कि "मेरा काम यहां पार्टी बनाना एवं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना है." अब जिस राज्य में मुख्यमंत्री का काम पार्टी बनाना ही होगा वहां शिवसेना ही क्यों, और भी सेनाएं सिर उठाएंगी.

—पवन कुमार नाड़े, दुर्गापुर (प. बंगाल)

कहां रही गरिमा

'तने तमंचों की तान' (31 जुलाई) में भागवत झा आजाद और शिवचंद्र झा के बीच बढ़ रहे विवादों का सटीक आकलन किया गया है. अगर यही हालात रहे तो बिहार में कांग्रेस अगला चुनाव कभी नहीं जीत पाएगी. घरेलू मामलों को विधानसभा में घसीटने से नेताओं की गरिमा ही घटी है.

—लालमोहर उपाध्याय, पटना (बिहार)

समाज का रवैया तो बदले

'बदनामी बन गई बाधा' (31 जुलाई) में वेश्याओं के बच्चों की समस्याओं का सही चित्रण किया गया है. सरकार को चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए हर जिले में एक स्कूल बनवाए जहां नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा का प्रबंध हो. समाज को भी रवैया सुधारना होगा. ये बच्चे सामाजिक बुराई का ही तो परिणाम हैं.

—नगमा तबस्सुम, औरंगाबाद (बिहार)

■ वेश्याओं के अभागे बच्चों के प्रति सरकार और समाज का नजरिया निश्चय ही चिंतनीय है. समाज का लांछन और अवहेलना ये मासूम क्यों भुगतें. ज्यादा ध्यान तो इन्हीं बच्चों की ओर दिया जाना चाहिए ताकि इन्हें अपराधी जीवन से बचाकर अच्छा नागरिक बनाया जा सके.

—कैलाश शर्मा, फरीदाबाद (हरियाणा)

■ वेश्याओं के ये अभागे बच्चे तो अनाथ बच्चों से भी ज्यादा बदनसीब हैं. अनाथ बच्चों के साथ समाज की सहानुभूति तो होती है, लेकिन इन बच्चों को इस नफरत से देखा जाता है मानो यह उनकी ही कोई गलती हो.

—पूर्ण चंद, दिल्ली

आखिर मानना पड़ा

'कठिन राह राजनीति की' (31 जुलाई) में यह पढ़ कर खुशी हुई कि नारायणदत्त तिवारी ने यह तो माना कि उत्तर प्रदेश के कामकाज के तरीके में बेहद सुधार की जरूरत है. यह भी विडंबना ही है कि देश को चार-चार प्रधानमंत्री देने वाला यह प्रदेश प्रशासनिक धांधलियों, अराजकता और भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है.

—बालेश जैन, बिजनौर (उ.प्र.)

तुलसी रामायण के हिन्दी भाषा की
घर-घर में रखी जाने वाली 1320 पृष्ठों वाली
संजीवनी टीका ग्रन्थ के लिए प्रसिद्ध प्रकाशक
खेमराज श्रीकृष्णदास वर्ष-प्रतिवर्ष
श्री विन्ध्या पेपर का ही सर्वोत्तम कागज
उपयोग में लेते रहे हैं...

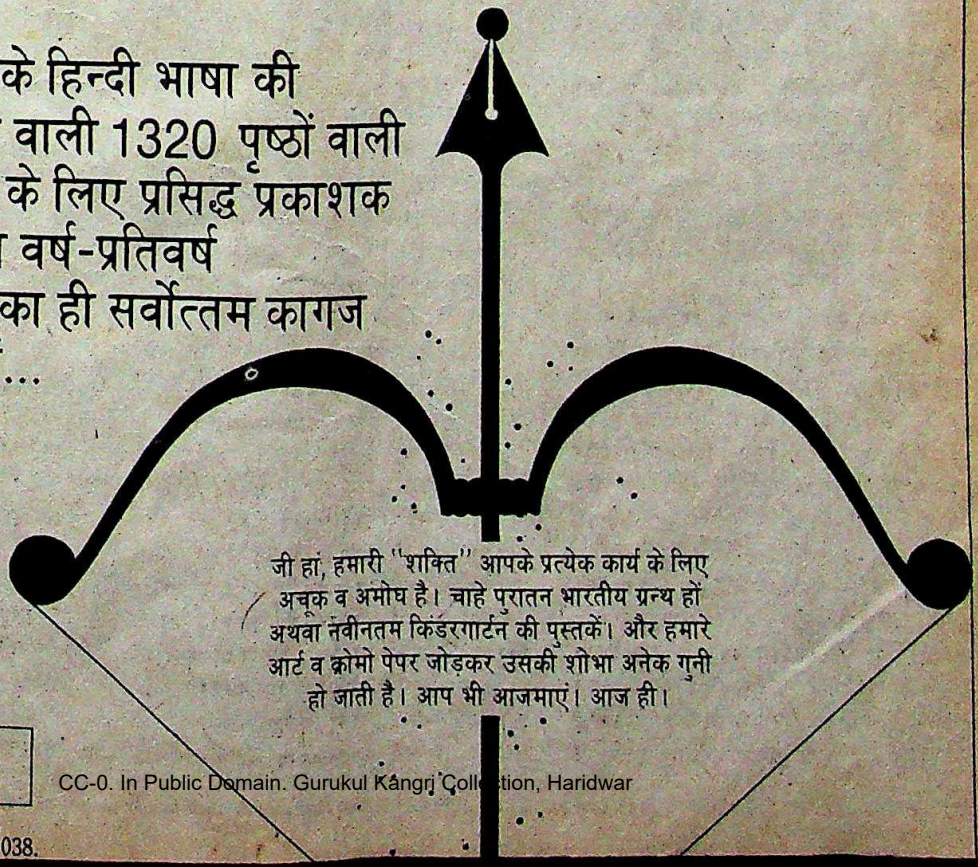

जी हां, हमारी "शक्ति" आपके प्रत्येक कार्य के लिए अचूक व अमोघ है। चाहे पुरातन भारतीय ग्रन्थ हों अथवा नवीनतम किंडरगार्टन की पुस्तकें। और हमारे आर्ट व क्रोमो पेपर जोड़कर उसकी शोभा अनेक गुनी हो जाती है। आप भी आजमाएं। आज ही।

SHREE विन्ध्या vindhya PAPER MILLS LTD.
Indian Mercantile Chambers,
Ballard Estate, Bombay - 400 038.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

भ्रष्टाचार का अभेद्य दुष्चक्र

भ्रष्टाचार का चरित्र नदी के समान होता है. उद्गम स्थल कहीं ऊपर और धारा अनवरत नीचे की ओर प्रवहमान. जैसे हमारी पवित्र गंगा इस भारत भूमि को सदियों से सींचती आई है, वैसे ही भ्रष्टाचार की यह अपवित्र गंगा भी पता नहीं कब से इस पावन भूमि को, इसके जनजीवन को प्रभावित करती रही है. लेकिन इधर अचानक इसकी धारा कहीं अधिक प्रबल, कहीं अधिक व्यापक और सर्वग्रासी लगने लगी है. घोटालों पर घोटालों के रहस्योद्घाटन, घूस और दलाली और गुप्त विदेशी खातों की चर्चाएं. और सत्ता दल में खलबली. और इन सबके ऊपर निरंतर बलवती होती यह धारणा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग — राजीव गांधी और उनके हमराज व हमसफर— गैरजवाबदेह हैं. और यह कि वे इसी तरह उलटफेर करते रहेंगे, फिर भी कुर्सियों पर बने रहेंगे.

यानी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, फूहडपन भी. और इसकी चर्चाएं महज दिल्ली के ऊंचे तबकों में ही नहीं, नीचे हर जगह हो रही हैं— सिरसा और पाली से लेकर गोधरा तक. इस कीचड़ को गींजने का काम ऊपर ही क्यों हो?

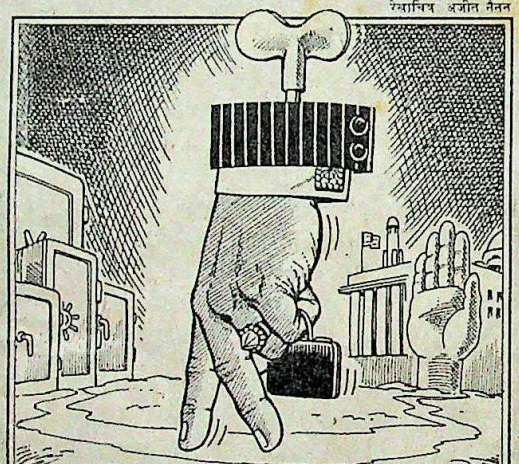
रेखाचित्र: अजीत नैनन

मगर ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी और सच्चरित्रता का स्वर्ग अचानक इस महान देश से लुप्त हो गया हो. यह दुष्कर्म और अपराध— घूसखोरी और दलालीखोरी— यहां तो कब का संस्थात्मक स्वरूप ले चुका है. जनता इसकी उतनी ही आदी हो चुकी है जितनी कि बच्चा मां के दूध का आदी होता है. पटवारी हो या स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अस्पताल के डॉक्टर हों या मुफस्सिल के अधिकारी, इंजीनियर हो या बीडीओ या फिर इलाके का विधायक, प्राय: हर किसी का यह कीचड़पुता चेहरा सदियों से वह झेलती आई है.

एक अजीब अदृश्य प्रक्रिया है जिसके तहत विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों का पैसा नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच गुजरते हुए लुप्त हो जाता है. और फिर रोना रोया जाता है 'अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था' का जिसमें साधनों और सेवाओं का अभाव सरकारी प्रयासों से जानबूझकर बनाया जाता है. लेकिन पाबंदियों, लाइसेंस, परमिट वगैरह को दरकिनार कर दें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं. इस व्यवस्था का भरपूर लाभ नौकरशाहों व नेताओं की 'समाजवादी' बिरादरी उठाती रही है.

इसके बावजूद अभी पांच वर्ष पहले तक स्थितियां कुछ भिन्न थीं, भले ही सरकार सिद्धांत के नाम पर एक विशाल जोंक की तरह समाज और अर्थव्यवस्था के उत्पादन तंत्र पर चिपटी हुई थी. फिर भी कोई बात थी जो केंद्र एक नैतिक सत्ता का आभास देता था. तब शायद यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बच्चा आकाशवाणी पर वैसा नारा लगा सकता है जैसा पिछले दिनों आकाशवाणी के पटना केंद्र से सुना गया, "गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है."

पिछले चंद वर्षों में उस नैतिक सत्ता का आभास मिटता गया है. ऊपर के तबके में भ्रष्टाचार फैलने का एक बड़ा कारण चुनाव लड़ने में और पार्टी ढांचे को बनाए रखने में बेहिसाब खर्च है. सत्ता और विपक्ष के अनुमानों के मुताबिक यह खर्च पांच गुना बढ़ गया है. कांग्रेस को पार्टी संगठन चलाने पर और पदाधिकारियों पर हर महीने एक करोड़ से कुछ ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं. और सभी विपक्षी पार्टियां भी मिलकर इस मद में करीब इतनी ही रकम खर्च करती हैं. 500 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च.

ऐसे में जाहिर है कि इस खर्च की रकम जुटाने के लिए नई व्यवस्था ईजाद करनी ही थी. राजीव के पदार्पण के बाद जो व्यवस्था उभरी है उसके तहत पार्टी के लिए चदा उगाहने का काम केंद्रीकृत हो गया है. पहले यह उगाही नीचे के स्तरों पर भी होती थी— पार्टी के विधायकों, सांसदों, प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा. आज चंदा उगाहने वाले लोग उद्योगपति के भेष में होते हैं. और इन नए 'उद्यमियों' की सत्ताधारियों से अच्छी सांठगांठ होती है. सौदे तो उनके पास किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत आते ही रहते हैं. इन सौदों का कुछ पैसा उनके 'व्यापार-धंधे' में लगता है और अधिकांश पार्टी के काम आता है. उनसे जब पैसा मांगा जाता है, वे तत्परता से हाजिर कर देते हैं. इसलिए जब वे धरे जाते हैं तो सत्ताधीश उनकी बलि देने से घबराते हैं. क्योंकि वे कई भेद जानते हैं इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है. यह 'अभेद्य दुष्चक्र' है.

यह सच है कि राजीव के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई ठोस सबूत नहीं है. उनके करीबी लोगों के खिलाफ जरूर परिस्थितिजन्य सबूत हैं. लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इसलिए आम धारणा यही है कि राजीव की इनसे मिलीभगत है. खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो और वित्त मंत्रालय की खुफिया एजेंसियां अब ऊपर वालों की करतूतों की लीपापोती में ही लगी हैं. और विधायिका प्रहरी नहीं, बल्कि कार्यपालिका की मानो दासी बन गई है. बोफोर्स मामले की जांच के लिए बनी संसदीय समिति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है.

इन सबका समाधान आखिर क्या हो? तत्काल तो ये उपाय किए ही जा सकते हैं— राजनैतिक दलों के कोष का खुला लेखा परीक्षण हो, औद्योगिक घराने पार्टियों को जो चंदा देते हैं उनके संबंध में कानून बनें, और चुनावों के लिए उम्मीदवारों को सरकारी सहायता देने का प्रावधान हो जैसा कि जर्मनी और अमेरिका में होता है. लेकिन जब तक दरबारबाजी, यारबाजी, पक्षपात, कुलीनवाद को, जिन्हें राजीव के चार वर्षों के शासन की विशेषताएं माना जाने लगा है, खत्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक कलंक की यह कालिख धुल नहीं पाएगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खुली नीति के सबक

● पंजाब में प्रचार माध्यमों के लिए खुली नीति अपनाकर भारत सरकार ने कई सबक सीखे हैं. इसी नीति के चलते विदेशी प्रेसवालों को भी अपेक्षाकृत गड़बड़ीवाले इलाकों में आने-जाने की आजादी दी गई. इसका सबसे बड़ा सबक तो यही है

कि प्रेस पर पाबंदी लगाने से अफवाहों और गलत खबरों को ही बढ़ावा मिलता है. लेकिन छूट देने से विदेशी प्रेस में कभी-कभार परेशान कर देने वाली खबरें तो छप जाया करती हैं लेकिन कुल मिलाकर निष्पक्ष और सही खबरनवीसी से सरकार की छवि ही सुधरती है.

इस तथ्य के मद्देनजर अब लुकिया ब्यूरो पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के दूसरे गड़बड़ीवाले इलाकों में विदेशियों की यात्रा पर लगी पाबंदी हटाने की सोच रहा है. इन इलाकों में एक लद्दाख भी है जिस पर चीन अपना दावा करता रहा है. संभव है यह मुद्दा जल्द ही फिर से उठे. एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, "इससे दुनिया को पता चलेगा कि हममें कितना आत्मविश्वास है और यह कि अपने इलाकों पर हमारा पूरा नियंत्रण है, भले ही दावा कोई करे." इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय सियाचिन की पहाड़ियों में पत्रकारों की यात्रा के नियमों को उदार बनाना चाहता है. पर विदेश मंत्रालय इस पर राजी नहीं है. उसका कहना है कि पत्रकारों के दौरों से पाकिस्तान भड़क उठेगा और फिर अपने कब्जे वाले 'आजाद' कश्मीर में ऐसे ही दौरे आयोजित करवाएगा. विदेश मंत्रालय इस समय प्रचार युद्ध में फंसना नहीं चाहता.

मिट्टी की पहचान

● अरुण सिंह जो कभी राजीव गांधी के सबसे करीबी सलाहकार थे, अब संसद से इस्तीफा देकर एकांतवासी हो गए हैं. उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा को भेजे अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने राजनीति में आकर बड़ी गलती की थी, क्योंकि वे उस मिट्टी के ही नहीं बने हैं जो इस मैदान में डट सके.

लगता है उन्हें अपनी मिट्टी की पहचान हो गई है. तभी शायद वे कुमाऊं की वन आच्छादित पहाड़ियों में जिंदगी बिता रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से वे हिमालय के आरक्षित वन क्षेत्र के बिनसर में टिके हैं. वहां उन्होंने दो कमरों की एक कुटिया किराये पर ली है जिसमें न पानी है, न बिजली. वहां कोई कार या उनकी जिप्सी भी नहीं पहुंच पाती. सड़क सिर्फ सरकारी गेस्ट

सभी कार्टून: अजीत नैनन

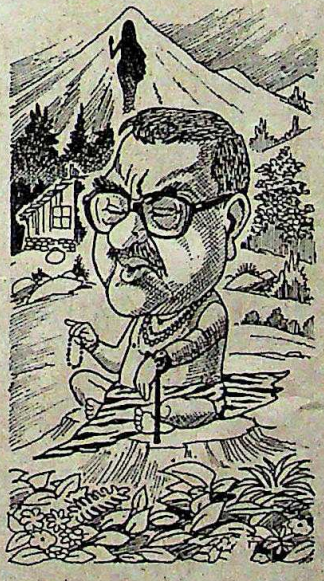

हाउस तक ही है. उसके आगे कुटिया तक जाने के लिए 45 मिनट की चढ़ाई पैदल चढ़नी पड़ती है. 45 वर्षीय अरुण सिंह अपनी बाकी जिंदगी पहाड़ी लोगों के बीच सामाजिक कार्य करते हुए बिताना चाहते हैं. जूता पॉलिश कंपनी के तेजतर्रार अधिकारी और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कभी सबसे असरदार मंत्री रहे व्यक्ति का यह नया रूप है तो अजूबा, मगर आज का सच भी.

पायलट की पूछ

● तख्त पर पायलट, यानी दिलचस्प संयोग! भूतल परिवहन राज्यमंत्री राजेश पायलट का मामला तो निश्चित रूप से कुछ

ऐसा ही लगता है. अभी पिछले दिनों वे हॉलैंड के सरकारी दौरे पर गए थे. वहां के उनके समकक्ष मंत्री ने उनसे पूछा कि क्या आपका उपनाम आपके धंधे के कारण रखा गया है. उनका अनुमान ठीक भी था. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान बमवर्षक विमानों से उड़ानें भरने वाले पायलट ने उन्हें बताया कि वे भारतीय वायुसेना में अफसर रह चुके हैं. इस पर मेजबान ने उनसे आग्रह किया कि वे एफ-16 जरूर उड़ाकर दिखाएं. पायलट का डॉक्टरी परीक्षण जमकर किया गया. जांच में उन्हें उड़ान के लिए फिट पाया गया. फिर क्या था. दो सीटों वाले प्रशिक्षण विमान में वे सवार हो गए. आसमान को चीरते हुए ऊपर गए, एक गोल चक्कर लगाया और लौट आए.

जब वे भारत लौटे तो भारतीय वायुसेना का निमंत्रणपत्र उनका इंतजार कर रहा था. अगर वे विदेश में एफ-16 उड़ा सकते हैं तो अपने देश में एकदम नया मिग-29 क्यों नहीं. पायलट समय की कमी का बहाना बनाकर टालमटोल तो कर रहे हैं लेकिन उम्मीद है इसी महीने कभी वे इस विमान पर उड़ान भरेंगे. वैसे पायलटों की पूछ भी तो इन दिनों बढ़ गई है.

जारी है सौदेबाजी

● तेजाब-सी तीखी जुबान वाले काशीपुर के विधायक अकबर अहमद 'डंपी' ने पिछले साल नारायणदत्त तिवारी की विधानसभाई सीट जीतकर संजय गांधी का परचम फहराए रखा था. उन्हीं 'डंपी' को अब कांग्रेस (इ) फुसलाने में लगी है. उनकी नेता मेनका गांधी तो जनता पार्टी में चली गई पर डंपी और उनके संजय मंच के समर्पित 'मंचियों' ने एकला चलने का ही फैसला किया था. डंपी 'वी.पी. सिंह और उनके हताश साथियों' की खुलकर आलोचना भी करते रहे हैं.

उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद तिवारी ने डंपी के एक खासमखास से संपर्क साधा ताकि उन्हें पटाया जा सके. तिवारी की समस्या यह है कि उन्हें जल्द ही विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा पर उन्हें इसके लिए कोई सुरक्षित

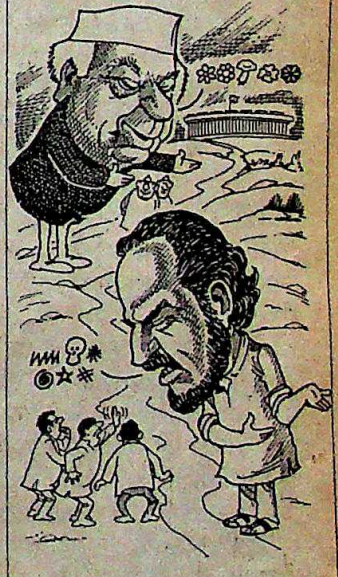

सीट नहीं मिल रही है. अगर तिवारी हार जाते हैं तो इंका के लिए भारी आफत खड़ी हो जाएगी. इसलिए बातचीत जारी है. सौदा तय हो रहा है कि डंपी तिवारी के लिए काशीपुर की सीट खाली कर दें यानी इस्तीफा दे दें तो बदले में उन्हें राज्यसभा की सदस्यता या फिर मंत्रिपद दे दिया जाएगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपकी चहेती पत्रिका
आपके दरवाज़े पर
न खरीदने का झंझट...
न खत्म होने का डर

इस सुविधा का लाभ उठाइए.
आपनी चहेती इंडिया टुडे
घर बैठे – नियमित पाइए,
न खरीदने जाने की ज़रूरत...
न अंक खत्म होने का डर,
इंडिया टुडे
समय से पहुंच जाए आपके घर !
बस कूपन भर कर भेज दीजिए,
देर मत कीजिए !

नाम _____
डाक पता _____
_____
_____
_____

मूल्य वार्षिक रु 120/-
भुगतान का माध्यम – चैक/मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट
कृपया चैक निम्नलिखित नाम पर बनाएं और इस पते पर भेजें
लिबिंग पीडिया इंडिया (प्रा.) लि
सबस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट थौमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. नं. 69, दिल्ली मथुरा रोड,
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

MILESTONES/IT/120

● मंत्रिमंडल में वो इतना बदलाव करते हैं. जनता तो सिर्फ एक पद पर बदलाव चाहती है. वही खाली कर दें—प्रधानमंत्री का पद.
■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *धर्मयुग*

● मैं उन बेइमानों में से नहीं हूं जो जोड़तोड़ की राजनीति करते हैं. मैंने धोखा खाना सीखा है, धोखा देना नहीं.
■ **फारूक अब्दुल्ला,** *रविवार*

● हमें एकाध महीने में ऐसे कागजात मिलेंगे जिनसे पता चलेगा कि ज्ञानी का सीधा संबंध देशद्रोहियों और देश को तोड़ने वालों से रहा है.
■ **के.के. तिवारी,** *दिनमान*

● वे (भागवत झा आजाद) अपने अलावा सबको बेइमान मानते हैं.
■ **बिहार के असंतुष्ट विधायक,** *नवभारत टाइम्स*

● मेरी सीधी कार्रवाइयों से मेरे निंदक भले नाराज हों, लेकिन मैंने बिहार के लिए जो कुछ किया है उस पर कायम हूं.
■ **भागवत झा आजाद,** *इंप्रिंट*

● तमिलनाडु के कांग्रेसी नेता अपने राज्य में शेर रहते हैं लेकिन दिल्ली आकर बिल्ली हो जाते हैं.
■ **सुब्रमण्यम स्वामी,** *पंजाब केसरी*

● कुछ लोग अपने आपको चौधरी समझते हैं. उनके ही इलाके में बच्चा मां को रो रहा है, मां बच्चे को रो रही है.
■ **जगदीश टाइटलर,** (दिल्ली में हैजा के मामले पर चर्चा के लिए कांग्रेस की एक बैठक में), *जनसत्ता*

● भारतीय खेलों का दीमक क्रिकेट है.
■ **गुरु हनुमान,** *स्वतंत्र भारत*

● अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है. और शायद जब तक मैं सब कुछ सीखकर पारंगत खिलाड़ी बनूं तब तक कहीं हॉकी खेलना ही न छोड़ना पड़ जाए.
■ **मुहम्मद शाहिद,** *स्पोर्ट्सवीक*

● कुछ दिन आजादी से घूम-फिर सकेंगे.
■ **अरुण गोविल,** (रामायण सीरियल की समाप्ति पर), *हिंदुस्तान*

● अभिनय का अनुभव से कुछ लेना-देना नहीं है. यह तो आपके भीतर होता है या फिर नहीं ही होता.
■ **श्रीदेवी,** *फिल्मफेयर*

● हर निजी चीज को एक्सपोज करने के मैं सर्वथा विरुद्ध हूं. इसी में चुंबन भी एक है.
■ **जयप्रदा,** *माया*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंदाजे बयां...

■ पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के बोट क्लब ने लंदन के हाइड पार्क का अवतार बनकर उन लोगों के दिलों पर मरहम का काम किया है जिनकी कोई सुनने वाला नहीं. आए दिन वहां केरल से लेकर

सभी कार्टून: मंजुला पद्मनाभन

कश्मीर तक और गुजरात से मणिपुर तक के विशाल इलाके से जुड़ी शिकायतों का अंबार देखने को मिलता रहता है. शिकायतें पेश करने के नए-नए अंदाज भी सामने आने लगे हैं. पिछले पखवाड़े राजधानी के नागरिकों को प्रदर्शनों की इस श्रृंखला में एक अनोखा करतब तो जरूर देखने को मिला लेकिन पुलिस हस्तक्षेप के कारण वे कहीं अधिक अनोखा करतब देखने से वंचित रह गए.

मामला भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के लगभग 100 कर्मचारियों का था जो कंपनी की ओर से लागू की गई नई सेवा शर्तों के खिलाफ प्रदर्शन करने दिल्ली आए हुए थे. प्रदर्शन के पहले दिन तो उन्होंने अपने-अपने मुंह पर पट्टी बांधकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन करके यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार उनके मुंह की रोटी छीन रही है. अगले दिन उन्होंने अपनी कमीजें उतारकर यह प्रदर्शन दोहराया. लेकिन तीसरे दिन जब प्रदर्शनकारी अपनी पतलूनें उतारकर अपने साथ हुए अन्याय की ओर लोगों का ध्यान खींचने की योजना बना रहे थे तब पुलिस ने उन्हें पतलूनों समेत जा पकड़ा और योजना को ठप कर दिया. पुलिस को डर था कि कहीं यह आंदोलन इससे भी अगले दौर में न प्रवेश कर जाए.

किस्सा कुर्सियों का

■ जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है वैसे-वैसे स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की समस्या भी विकराल रूप लेती जा रही है. खास तौर से पब्लिक स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए तो 'दान' और 'कैपिटेशन फीस' के आंकड़े अब लाखों की सीमा को छूने लगे हैं. आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तो हालत अब यहां तक जा पहुंची है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों के भावी ससुर दहेज में कैपिटेशन फीस भी देने लगे हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली यह दान महिमा भला प्राइवेट संस्थानों तक ही सीमित रह जाए, यह कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश के रायपुर शहर में नगरपालिका की ओर से संचालित एक हाईस्कूल ने इस महिमामंडित क्षेत्र में अपनी कुर्सी बिछाकर देश भर के सरकारी स्कूलों का नए ढंग से मार्गदर्शन करने का फैसला किया है. एक समाचार के अनुसार इस स्कूल के प्रबंधकों ने अपने यहां कुर्सियों की कमी की समस्या हल करने के लिए एक नया नुस्खा निकाला है. इस साल दाखिले के समय यह घोषणा कर दी गई कि दाखिला लेने के इच्छुक उस विद्यार्थी के आवेदन पर अधिक सहानुभूति से विचार किया जाएगा जो प्रवेश पत्र

के साथ स्कूल को दो कुर्सियां भी पेश करेगा. इसका नतीजा यह हुआ कि दाखिला लेने आए विद्यार्थी हाथ में प्रवेश पत्र और सिर पर दो-दो कुर्सियां लेकर चले आए.

अनोखी साजिश

■ ऐसे किस्से नए नहीं रह गए कि श्मशान घाट की ओर जाती शवयात्रा को बीच रास्ते में छोड़ कोई मुर्दा उठ खड़ा हुआ हो. लेकिन पिछले पखवाड़े बिहार के झुमरी तलैया में पुलिस का वास्ता

एक ऐसे मुर्दे से पड़ा जो पुलिस विभाग की होशियारी का राम-नाम-सत्य करने के लिए थाने ही जा पहुंचा.

किस्सा यह है कि आधी रात के समय रोते-पीटते लोगों का एक हुजूम थाने में जा धमका. वे लोग अपने कंधे पर चारपाई लादे हुए थे जिस पर सफेद कपड़े में लिपटी और खून से सनी एक लाश रखी हुई थी. ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने आंसू टपकाते हुए लोगों को सांत्वना दी और लाश को एक ओर रखकर रिपोर्ट लिखवाने को कहा. लोगों ने अधिकारी को बताया कि उनके गांव के दो व्यक्तियों ने इस व्यक्ति की हत्या की है इसलिए हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. पुलिस अधिकारी ने उनकी बात सुनने के बाद कपड़ा हटवाया और लाश का मुआयना शुरू किया. जब उसने मुर्दे की नब्ज देखना शुरू की तो शिकायती धीरे-धीरे खिसकने लगे. इसी बीच मुर्दे में भी हरकत हुई और वह भी अधिकारी से हाथ छुड़वाकर और कफन उतारकर भाग खड़ा हुआ. अधिकारी ने तुरंत शोर मचाया और सिपाहियों ने 'मुर्दे' समेत दो और लोगों को धर दबोचा. बाद में पता चला कि यह सारा षड्यंत्र दो लोगों को हत्या के मामले में फंसाने के लिए रचा गया था.

सदस्यता जरूरी

■ दूरदर्शन के सीरियल इतिहास में 'रामायण' को उसकी लोकप्रियता के अलावा उससे जुड़े किस्सों की वजह से भी याद किया जाएगा. कभी किसी रामायण प्रेमी बंदर की वजह से; कभी ग्राहक को मझधार में छोड़कर टीवी देखने चले गए नाई की वजह से; कभी मूर्छित राम के प्रति दुख दिखाने वालों के उपवास के कारण या फिर बिजली फेल होने पर हुल्लड़-बाजी की वजह से यह सीरियल डेढ़ साल तक लगातार चर्चा का केंद्र बना रहा. पिछले दिनों सीरियल के अंतिम दौर में रावण की मृत्यु ने इन किस्सों की श्रृंखला में एक और किस्सा जोड़ दिया.

रावण वध के अगले सप्ताह जब महाराष्ट्र के धरनगांव की म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य अपनी बैठक में पहुंचे तो विषय सूची में शामिल एक मुद्दे ने सबको चौंका दिया. एक सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया था कि टीवी सीरियल में 'रावण' की मृत्यु पर सदन में शोक प्रकट किया जाए. इस पर कुछ सदस्यों ने इसे अधर्म पर धर्म की जीत बताते हुए प्रस्ताव को रद्द करने की बात कही तो कुछ ने रावण की भूमिका निभाने वाले कलाकार अरविंद त्रिवेदी के शानदार अभिनय का हवाला देते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया. सभापति ने एक नायाब

दलील ढूंढ़ निकाली. उन्होंने प्रस्ताव को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि रावण कमेटी का सदस्य नहीं इसलिए उसके निधन पर प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी नहीं.

—संकलन: विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'खबर' देती खबरें

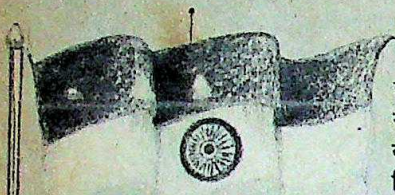

आजादी के चार दशक पूरे कर लिए भारत ने पिछले पखवाड़े—उथलपुथल वाले चार दशक, जिन्होंने हमें आज इस दुरावस्था में ला खड़ा कर दिया है. पूरे देश में राष्ट्रीय गीत गूंजते रहे, प्रगति के प्रशस्तिगान हुए, और सावनी बयारों के संग लहराते तिरंगे के साथ-साथ देशभक्ति की उमंग भी लोगों के दिलों में लहराई. गौरवशाली अतीत का और आज की उपलब्धियों का बढ़-चढ़ कर बखान किया गया.

रेखांकन: पिअली दत्त गुप्ता

एक वक्त था जब यह दिवस राष्ट्रीय गौरव और एकता का बोध कराता था. और लाल किले के प्राचीर से गूंजती प्रधानमंत्री की आवाज आस्था, आशा और विनम्रता के भाव जगाती थी. आज प्रधानमंत्री का भाषण घिसे-पिटे वायदों और संदेहास्पद उपलब्धियों की तोतारटंत भर रह गया है. आत्म गौरव और राष्ट्र-भक्ति का भाव लुप्त हो गया है. बच गई हैं सिर्फ भविष्य के बारे में आशंकाएं.

इस दुरावस्था के कारणों के पंडिताऊ राजनैतिक विश्लेषण की जरूरत नहीं. जवाब पिछले पखवाड़े अखबारों के पहले पन्नों पर साफ पढ़े जा सकते हैं:—

29 जुलाई: प्रधानमंत्री के बिलकुल करीबी सतीश शर्मा के दोस्त, दिल्ली के एक व्यापारी ललित सूरी से संबंधित एक घोटाले का पर्दाफाश. कमीशनखोरी का एक और मामला! सरकार इसमें किसी मिलीभगत से इनकार करती है.

29 जुलाई: महामारी से 200 लोगों की मृत्यु और अवैध बस्तियों से संबंधित प्रशासनिक घोटालों के कारण दिल्ली के उपराज्यपाल की छुट्टी. और उत्तराधिकारी के रूप में पूर्व विदेश सचिव रोमेश भंडारी की नियुक्ति.

30 जुलाई: गुजरात में पुलिसवालों का हफ्ते भर चला आंदोलन समाप्त. मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी की कुर्सी जाते-जाते बची.

30 जुलाई: पंजाब में शिवसेना के एक नेता सहित छह लोगों की हत्या.

31 जुलाई: नगालैंड में 13 इंका विधायकों का पार्टी से इस्तीफा. छह महीने में ही इंका सरकार अल्पमत में, महज इसलिए कि मुख्यमंत्री की 'ईमानदारी' उन्हें रास नहीं आई.

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण घिसे-पिटे वायदों की तोता-रटंत भर रह गया है. आत्म गौरव और राष्ट्रभक्ति का भाव कहीं लुप्त हो गया है

1 अगस्त: गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा राजीव गांधी और बूटा सिंह की हत्या की 'अंतरराष्ट्रीय साजिश' का रहस्योद्घाटन. इसका पता पाकिस्तान से किसी सिख आतंकवादी द्वारा पंजाब के अपने साथी आतंकवादियों को लिखी चिट्ठी से चला.

2 अगस्त: श्रीनगर में बम विस्फोट. सुराग का अता-पता नहीं.

3 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और केहर सिंह को मौत की सजा की पुष्टि. तीसरे अभियुक्त बलबीर सिंह को, जिसे नीचे की दो अदालतों ने अपराधी करार दिया था, बरी करने का फैसला.

4 अगस्त: आयकर विभाग की आम माफी योजना के तहत अमिताभ बच्चन द्वारा एक करोड़ रुपए वार्षिक आय की घोषणा.

5 अगस्त: अन्नाद्रमुक के एक घटक की नेता जयललिता द्वारा असंतुष्टों का निष्कासन. असंतुष्टों द्वारा जयललिता का निलंबन.

6 अगस्त: फरीदाबाद में चुनावी हिंसा में भागीदारी के आरोप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ एफआइआर दर्ज.

6 अगस्त: बिहार में नौका दुर्घटना में 500 के डूबने की आशंका.

6 अगस्त: रोडे सहित तीन मुख्यग्रंथी रिहा और तुरंत गिरफ्तार.

7 अगस्त: सात विपक्षी दलों के राष्ट्रीय मोर्चे का गठन. नंदमूरि तारक रामराव अध्यक्ष और विश्वनाथ प्रताप सिंह संयोजक.

7 अगस्त: नगालैंड विधानसभा भंग, राष्ट्रपति शासन लागू.

स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो!

—दिलीप बॉब

ललित सूरी

रोमेश भंडारी

नंदमूरि तारक रामराव

होकिशे सेमा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मस्ती का आलम!

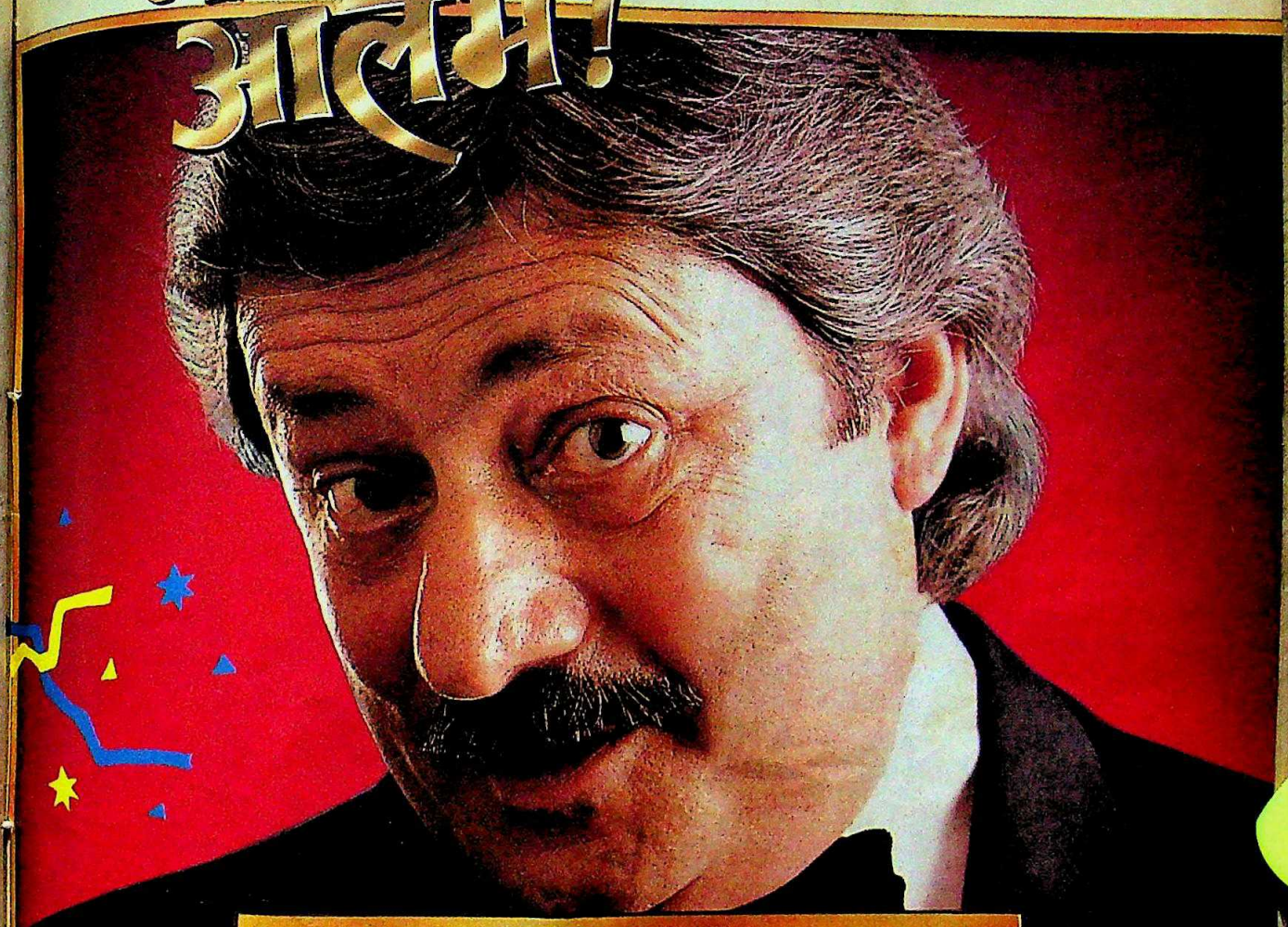

PARAG ZARDA

अपने हर पल को और मज़ेदार बनाइए, पराग ज़र्दे के संग।

इसका अनोखा स्वाद बेहतरीन तम्बाकू के लाजवाब मेल का नतीजा है — जो उसी सावधानी से बनाया जाता है जैसे आपका मनपसन्द पान पराग।

बस, अपनी पसन्द का ज़र्दा चुनिए, 110 या 50 न० — और पराग ज़र्दे की 'मस्ती' और ताज़गी का आनन्द लीजिए।

पराग® ज़र्दा

वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कोठारी उत्पादन

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजीव गांधी फीकी पड़ गई

पहले चमक-दमक धुंधलाई. फिर 'श्रीमान स्वच्छ' वाली छवि बदरंग होने लगी. लेकिन नेहरू-गांधी परिवार के युवा वारिस, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राजनैतिक भाग्य ने चाहे जितने पलटे खाए हों, उनसे लोगों का मोहभंग नहीं हुआ था. भले ही राजीव और उनकी पार्टी ने जनता के साथ बांदी सरीखा व्यवहार किया पर कुल मिलाकर लोग प्रधानमंत्री और इंका के वफादार ही बने रहे.

ये बातें इतिहास लिखने वाले अंदाज में लिखी गई है क्योंकि मतदाताओं के मन में जिस नाटकीय तरीके से बदलाव आ गया है उससे ये बातें पुराने जमाने की ही लगती हैं. राजीव और उनकी पार्टी इंका खतरनाक राजनैतिक ढलान पर एकदम नीचे की ओर फिसलने लग गई है.

जून में हुए उपचुनावों ने सत्तारूढ़ दल के भविष्य के पूर्वसंकेत दे दिए. ज्यादातर लोगों को भी ऐसा भरोसा नहीं था. लेकिन सात में से चार संसदीय सीटों—गोधरा, फरीदाबाद, इलाहाबाद और सिरसा—में तो इंका के प्रत्याशी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवारों के हाथों बुरी तरह पराजित हो गए.

ज्यादा संभावना है कि ये अपशकुन के संकेत थे. अगस्त के पहले हफ्ते में 'इंडिया टुडे' ने जो जनमत संग्रह कराया उससे यही संदेश मिलता है कि राजीव को चुनने के बाद से पहली बार जनता उन्हें उखाड़ फेंकने के मूड में है. अगर अभी चुनाव हों और विपक्ष में 1977 जैसा एका हो तो इंका को 223 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी. और अगर 1984 की तरह विपक्ष बिखरा रहे तो भी इंका को 297 सीटें ही मिल पाएंगी.

कितनी जबरदस्त कमी आ गई. यह बदलाव पिछले छह महीनों में ही हुआ लगता है. इस साल फरवरी में कराए गए जनमत संग्रह के समय राजीव की स्थिति काफी अच्छी थी. अगर उस समय चुनाव होते तो उनकी पार्टी को 345 सीटें मिलतीं. उससे पहले (अगस्त 1987) के जनमत संग्रह में 323 सीटें मिलने की उम्मीद थी. यानी 1984 के चुनाव की भारी जीत के बाद राजीव की लोकप्रियता में जो कमी आई, वह दूर होने लगी थी. फिर अब लोकप्रियता में अचानक इतनी गिरावट की वजह क्या है?

लगता है कि अब लोग राजीव को

प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चमक-दमक

आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक मोर्चे पर नाकाम मानने लगे हैं. मूल्यवृद्धि से पूरा देश परेशान रहा है. 1984-85 की तुलना में थोक कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है. प्याज की कीमत में 106.3 फीसदी, अरहर दाल में 69.2 फीसदी, आलू में 60 फीसदी, टमाटर में 70 फीसदी, वनस्पति में 56.6 फीसदी, सरसों के तेल में 70.7 फीसदी और गोभी में 68.3 फीसदी वृद्धि हुई है.

राजीव की साख में भी शायद इतनी ही तेजी से कमी आई है और उनकी छवि भी इतनी ही धुंधलाई है. इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता पार्टी को मुख्य चुनौती देने वाले वी.पी. सिंह ने जनसंपर्क के मामले में प्रधानमंत्री से बाजी मार ली है. वे बोफोर्स और एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों वाले मसले और इनकी खरीद में राजीव के दोस्तों की संदेहास्पद भूमिका के बारे में आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे हैं. इन बातों पर अब सिर्फ शहर के ही नहीं, गांव के लोगों को भी चिंता है.

हाल के उपचुनावों में सभी विपक्षी उम्मीदवारों द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना अकारण ही नहीं था. शासक दल के खिलाफ यह एक कारगर हथियार साबित हुआ. लोगों के मन में यह बात बैठ गई लगती है कि उच्च पदों पर बैठे लोग आर्थिक लाभ तो लेते ही हैं, गलती करने पर अपनी रक्षा के लिए पद का दुरुपयोग भी करते हैं.

अभी तक इंका एकजुट रही है लेकिन पार्टी के अंदर नाराजगी है. शायद बची खुशी राजनैतिक नैतिकता के कारण ही ऐसा है. पर ऐसे लोग, फिलहाल ही सही, गलती करने वाले मजबूत नेताओं के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं. अप्रैल में मरैमलै नगर में इंका महासमिति का जो अधिवेशन हुआ उसमें चापलूसी का प्रदर्शन और अपनी बहादुरी का बखान तो हुआ ही, यह भी लगा कि इंका अपने नेता की छवि पर मुग्ध भी है.

फिर भी पार्टी को कमजोर कर रहे 'रोग' साफ दिख रहे हैं. इनका इलाज नहीं किया गया तो लाख पैसा खर्च करने, मेले लगाने या अपना गुणगान करने भर से इन्हें छुपाया नहीं जा सकता. सच यह है कि इंका में अब राजनैतिक मैदान में टिकने की सामर्थ्य चुकती जा रही है. यह संगठन वस्तुतः अब निष्क्रिय पड़ गया है. अनेक प्रदेश इंका कमेटियां भी निष्क्रियता के मकड़जाल में फंसी हैं. लगता नहीं कि वे उत्साह और भरोसा अर्जित कर रहे विपक्ष का मुकाबला कर पाएंगी. यह बात भी पिछले उपचुनावों में साफ तौर पर दिखाई दी.

ज्यों-ज्यों राजीव के राजनैतिक विकल्प सिमटते जा रहे हैं, वे गद्दी बचाने की लड़ाई पर ही पूरा जोर लगाते दिखते हैं. लोग इस बात पर खास गौर कर रहे हैं कि हर किसी को खुश रखने के चक्कर में उन्हें कमलाकांत तिवारी जैसे लोगों को भी मंत्री बनाना पड़ा,

राजीव को चुनने के बाद पहली बार जनता उन्हें उखाड़ फेंकने के मूड में है. अगर अभी चुनाव हो और विपक्ष में 1977 जैसा एका हो तो इंका को 223 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी. 1984 की तरह विपक्ष बिखरा हो तो भी इंका 297 सीटें ही ले पाएगी

जिन्हें खुद उन्होंने बाहर किया था. लोग इसे राजनैतिक कमजोरी का निश्चित संकेत मानते हैं. राज्यसभा के लिए मुश्किल से टिकट पाने वाले कल्पनाथ राय को भी मंत्री बनाने के बारे में लोगों का यही मानना है.

दरअसल वे राजनैतिक तौर पर विवश हो गए लगते हैं. लोग भी यह सब देख रहे हैं. और वे यह देखकर भी परेशान हैं कि अब प्रधानमंत्री इस्तीफे भी स्वीकार नहीं कर पाते. पहले उन्हें इस काम में कोई हिचक नहीं होती थी. गोधरा उपचुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए गुजरात प्रदेश इंका अध्यक्ष अहमद पटेल ने इस्तीफा दे दिया था. अभी तक यह स्वीकार नहीं हुआ है. उत्तर प्रदेश में भी महावीर प्रसाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के कई महीने बाद ही नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुना जा सका.

और मुख्यमंत्रियों को बदले जाने पर क्या होता है? पिछले करीब एक साल के अंदर असंतुष्टों को शांत करने और आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के मुख्यमंत्री बदले गए. नतीजतन नए मुख्य-मंत्रियों से नाराजगी उलटे और बढ़ गई. उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के साथ ऐसी बात नहीं है पर यह राज्य भी चुनावी दृष्टि से इंका के लिए अधिक असुरक्षित लगता है.

राजस्थान में हरिदेव जोशी के मुख्य-मंत्रित्व काल में ज्यादा असंतुष्ट नहीं थे. लेकिन उनको हटाने और शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाने से असंतुष्टों की संख्या बढ़ गई. मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह दुबारा पहुंचे नहीं कि मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया की जोड़ी उनके खिलाफ पूरे राज्य में हवाई दौरा कर आई. बिहार में आलाकमान ने भागवत झा आजाद को वहां के असंतुष्टों को शांत करने के लिए भेजा था. अब आजाद खुद ही असंतुष्टों का निशाना बन गए हैं. पिछले पखवाड़े उन्हें हटाने की मांग को लेकर 50 विधायक दिल्ली पहुंच गए थे.

शासक दल जहां लड़खड़ाता जा रहा है वहीं विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं. लगता है कि इस बार वे भी एकता के प्रति गंभीर हैं. इससे उनकी साख बढ़ेगी ही. इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि सरकार का भोंपू माने जाने वाले दूरदर्शन ने पिछले पखवाड़े अपने समाचारों में विपक्षी एकता के बारे में विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किया.

इसके बावजूद असलियत यही है कि जो विपक्ष राजीव के लिए सबसे बड़ा खतरा है उसी पर उनकी आस भी टिकी है. चूंकि विपक्षी नेताओं को सत्ता मिलती नजर आ रही है इसलिए वे एक होने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अभी भी उनमें मतभेद हैं, उन्होंने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया है और अभी भी वे एक-दूसरे की खिंचाई करने से बाज नहीं आ रहे. इस प्रक्रिया में वे अलग भी हो सकते हैं. राजीव की समस्या यह है कि 'श्रीमान स्वच्छ' के बाद अब उनकी कोई (अच्छी या बुरी) छवि ही नहीं रह गई है. अगर वे अपनी छवि बनाने में कामयाब रहे तो उन्हें अभी भी कुछ लाभ हो सकता है.

पहले जब कभी राजीव और उनकी पार्टी जनमत संग्रह में एकदम आगे नजर आ रही थी तो इसका कारण था—विकल्प का अभाव. लेकिन आज विपक्षी एकता का सूचकांक बहुत ऊपर पहुंच गया है. लगता है विकल्प आखिर उभर रहा है. और इसका मतलब है विकल्पहीनता की स्थिति में जीतने को तैयार बैठी इंका की पराजय.

—इंद्रजीत बधवार और प्रभु चावला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनमत संग्रह
कांग्रेस (इ)

तेजी से घटती

इंडिया टुडे ने प्रमुख और स्वतंत्र बाजार अनुसंधान कंपनी 'मार्ग' (मार्केटिंग ऐंड रिसर्च ग्रुप) को देश भर में वैसा ही व्यापक जनमत संग्रह करने का जिम्मा सौंपा था जैसा पिछले आम चुनाव से पहले अंग्रेजी 'इंडिया टुडे' ने कराया था. छह महीने के अंतराल में 'मार्ग' से कराए जाने वाले जनमत संग्रह की शृंखला का यह तीसरा संग्रह है.

2 से 7 अगस्त के बीच मार्ग के 100 से ज्यादा सर्वेक्षणकर्ताओं ने देश भर के 200 से ज्यादा गांवों और शहरों में जाकर 13166 मतदाताओं की राय पूछी. इस भारी-भरकम अभियान का निरीक्षण 'मार्ग' की ज्योति सिंह और सुनीता वेंकटरामन ने किया.

मशहूर चुनाव विशेषज्ञ प्रणय राय ने जनमत संग्रह के लिए 29 चुनाव क्षेत्र चुने. इस जटिल काम में अनुसंधान विषयक सहायता ललिता घोष और नम्रता हरीश ने प्रदान की.

इस जनमत संग्रह में सिर्फ यही पता नहीं किया गया है कि अगर मध्यावधि चुनाव हुए तो मतदाता किसे वोट देंगे, बल्कि अनेक मौजूदा विवादों और राजनैतिक दिलचस्पी वाले मुद्दों पर भी लोगों की राय ली गई है. इनसे नतीजे निकाले हैं प्रणय राय और 'मार्ग' ने.

राजीव गांधी के राज पर दुखद चुनावी अंत का खतरा मंडरा रहा है. विकल्प न रहने का लाभ अब प्रधानमंत्री और इंका को नहीं मिलने वाला. नवीनतम जनमत संग्रह के अनुसार विपक्षी दल एकजुट हो जाएं और मध्यावधि चुनाव होने पर भी एक बने रहें तो केंद्र में सत्ता परिवर्तन की भारी संभावना है. इंका के लिए इससे भी बुरी खबर है. विपक्ष यदि कुछ हद तक बंटा रहा तब भी सत्तारूढ़ पार्टी बहुत थोड़ा ही बहुमत पा सकेगी.

इंडिया टुडे-मार्ग जनमत संग्रह के नतीजे बताते हैं कि अगर 27 जुलाई से 2 अगस्त 1988 के बीच चुनाव हुआ होता तो इंका को लोकसभा की 542 में से 297 सीटें ही मिलतीं. उसे इतनी यानी कुल सीटों के आधे से सिर्फ 26 ज्यादा सीटें भी उसी स्थिति में मिलतीं जब विपक्ष 1984 की तरह बंटा रहता.

लेकिन विपक्षी दल 1977 की तरह एकजुट होकर लड़ते तो इंका को सिर्फ 223 सीटें ही मिलतीं और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाला मोर्चा 300 से अधिक सीटें ले जाता.

इस जनमत संग्रह से यह भी पता चलता है कि कई वर्षों में पहली

लोकसभा में इंका की ताकत

तालिकाएं: राजीव मदान

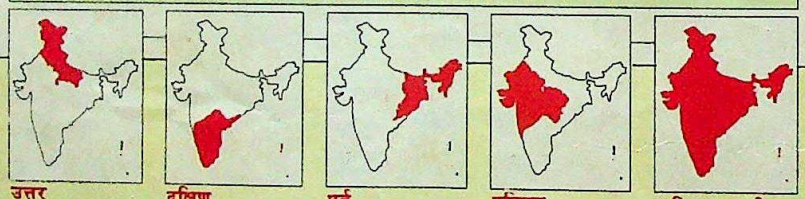

उत्तर
126 सीटें

राज्य	सीटें
हरियाणा	10
हिमाचल	4
जम्मू-कश्मीर	6
पंजाब	13
उत्तर प्रदेश	85
चंडीगढ़	1
दिल्ली	7

दक्षिण
132 सीटें

राज्य	सीटें
आंध्र	42
कर्नाटक	28
केरल	20
तमिलनाडु	39
अंडमान-निकोबार	1
लक्षद्वीप	1
पांडिचेरी	1

पूर्व
142 सीटें

राज्य	सीटें
अरुणाचल	2
असम	14
बिहार	54
मणिपुर	2
मेघालय	2
मिजोरम	1
नगालैंड	1
ओडीसा	21
सिक्किम	1
त्रिपुरा	2
प. बंगाल	42

पश्चिम
142 सीटें

राज्य	सीटें
गोवा	2
गुजरात	26
मध्य प्रदेश	40
महाराष्ट्र	48
राजस्थान	25
दादरा-नगर हवेली	1

अखिल भारतीय
542 सीटें

	इंका की कुल सीटें	लोकसभा की कुल सीटें	% सीटें
1988 (अगस्त जनमत संग्रह)	**49**	**56**	**76**	**116**	**297**	**542**	**54.8**
1988 (फरवरी जनमत संग्रह)	74	76	86	109	345	542	63.7
1987 (अगस्त जनमत संग्रह)	65	79	79	100	323	542	59.6
1984	114	71	96	134	415*	542	76.6

*1985 में हुए चुनाव में पंजाब और असम में जीते स्थान शामिल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोकप्रियता

बार विपक्ष सरकार बना सकने के काफी करीब पहुंच गया है. 1984 के चुनाव में इंका लहर इतनी तेज थी कि तब अगर विपक्षी एकजुट भी रहते तो वे इंका को मिली 415 सीटों की संख्या 363 तक ही ला पाते— फिर भी इंका का दो तिहाई बहुमत रह ही जाता. इस जनमत संग्रह का संदेश यही है कि विपक्षी अगर एकजुट रहे तो अगले चुनाव में उनकी बारी आ सकती है. लेकिन वे बंटे रहे तो गए काम से.

पर विपक्षी एकता का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि सात मध्यमार्गी पार्टियां मिलकर 'राष्ट्रीय मोर्चा' बना लें. व्यापक एकता के बिना उनकी कोशिशों का भी बहुत फल नहीं निकलेगा. जैसे, अगर उत्तर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय मोर्चा जैसी दो मजबूत पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ें तो वे न सिर्फ एक दूसरे के वोट काटेंगी बल्कि इंका विरोधी वोट भी बांट देंगी. इस तरह हर चुनाव क्षेत्र में दो मजबूत विपक्षी उम्मीदवार होने से इंका की जीत पक्की हो जाएगी.

सभी चार्ट: बी.के. शर्मा

विपक्षी एकता का स्तर

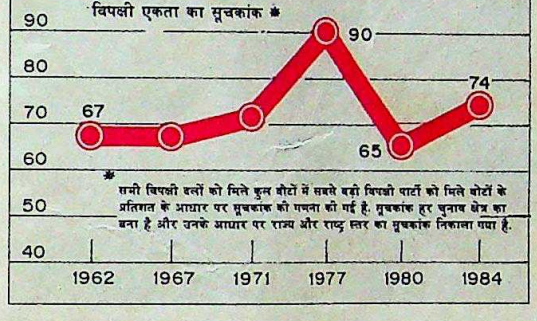

* सभी विपक्षी दलों को मिले कुल वोटों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को मिले वोटों के प्रतिशत के आधार पर सूचकांक की गणना की गई है. सूचकांक हर चुनाव क्षेत्र का बना है और उनके आधार पर राज्य और राष्ट्र स्तर का सूचकांक निकाला गया है.

जनमत संग्रह से पता चलता है कि आर्थिक परेशानियों या कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर नाराजगी तो नहीं बढ़ी है लेकिन छह महीने पहले कराए गए इंडिया टुडे-मार्ग के जनमत संग्रह से लेकर अब तक राजीव गांधी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आ गई है. प्रधानमंत्री अभी भी वी.पी. सिंह समेत सभी विपक्षी नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय हैं लेकिन इन लोगों की लोकप्रियता के बीच का फासला कम होता जा रहा है. प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के बारे में मतदाताओं की राय में बदलाव आया है. राजीव के लिए इस जनमत संग्रह का यह नतीजा चिंताजनक है कि उन्हें गरीब समर्थक की तुलना में अमीर समर्थक मानने वालों की संख्या अधिक है.

विपक्ष के लिए भी कुछ चिंतनीय मुद्दे हैं. करीब दो तिहाई मतदाताओं का मानना है कि अगर विपक्षी दल एक हो भी गए तो भी उनमें टूट हो सकती है. इतना ही नहीं, एक तिहाई मतदाता ही जानते हैं कि इलाहाबाद उपचुनाव में कौन जीता. करीब तीन चौथाई ग्रामीण मतदाताओं को वी.पी. सिंह की जीत की जानकारी नहीं. वैसे जनमोर्चा को जानने वालों का प्रतिशत आज छह माह बाद 20 से बढ़कर 34 भले ही हो गया हो लेकिन साल भर पुराने जनमोर्चा के हिसाब से जागरूकता का यह स्तर काफी कम है. विपक्ष के शस्त्रागार के सबसे महत्वपूर्ण हथियार भ्रष्टाचार को मतदाता अब उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानते जितना कि साल भर पहले मानते थे.

लोकसभा में इंका की सीटें

रेखांकन: मंजुला पद्मनाभन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रधानमंत्री का कामकाज

		अच्छा	औसत	बुरा
उत्तर		28	31	41
दक्षिण		49	31	20
पूर्व		32	31	37
पश्चिम		39	39	22
अखिल भारतीय	अग. 88	38	33	29
	फर. 88	43	35	22
	अग. 87	34	37	29

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

प्रधानमंत्री: कामकाज बनाम उम्मीदें

		उम्मीद से अच्छा	उम्मीद से बुरा	उम्मीद के अनुरूप
उत्तर		22	52	26
दक्षिण		42	26	32
पूर्व		25	51	24
पश्चिम		35	34	31
अखिल भारतीय	अग. 88	32	39	29
	फर. 88	36	32	32
	अग. 87	30	40	30

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

राजीव के बारे में राय बिगड़ी

कामकाज के मामले में प्रधानमंत्री कैसे हैं, इस बारे में लोगों की राय फरवरी 1988 के जनमत संग्रह में सुधरी थी. लेकिन अब यह गिरकर अगस्त 1987 के स्तर पर पहुंच गई है. उनके कामकाज को खराब बताने वालों की संख्या फरवरी के 22 फीसदी से बढ़कर 29 फीसदी हो गई है.

बढ़ता फासला

प्रधानमंत्री के कामकाज के बारे में तो लोगों की राय खराब हुई ही है, मतदाताओं की उम्मीदों और उनके कामकाज के बीच अंतर बढ़ा है. करीब 40 फीसदी मतदाताओं को लगता है कि उनका कामकाज उम्मीद से बदतर रहा है. उत्तरी और पूर्वी इलाकों में मतदाताओं का मोहभंग ज्यादा हुआ है.

राजीव की बढ़त घटी

विपक्षी नेताओं की ताकत जानने के लिए जनमत संग्रह में लोगों से पूछा गया कि राजीव गांधी और वी.पी. सिंह में बेहतर प्रधानमंत्री कौन होगा. राजीव के मुकाबले प. बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और कर्नाटक के (तत्कालीन) मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के बारे में भी राय पूछी गई. जब से जनमत संग्रह का यह क्रम शुरू हुआ है, पहली बार उत्तर में वी.पी. सिंह ने बढ़त हासिल की है. उन पर राजीव की बढत फरवरी '88 में 45 फीसदी थी जो अब 19 ही रह गई है. पिछली बार राजीव को इंकाई मतदाताओं का पूरा और विपक्षी मतदाताओं का आंशिक बहुमत मिला था. इस बार वी.पी. सिंह ने विपक्षी मतदाताओं के बीच उनसे बाजी छीन ली है.

वैसे हेगड़े और बसु राजीव गांधी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती नहीं हैं लेकिन फरवरी '88 के बाद उनकी स्थिति भी सुधरी है. इस बीच 'बुरे नक्षत्रों' के फेर में पड़े हेगड़े की लोकप्रियता भी कोई कम नहीं हुई है जबकि बसु राजीव के खिलाफ अभी तक की सबसे अच्छी स्थिति में उभरे हैं.

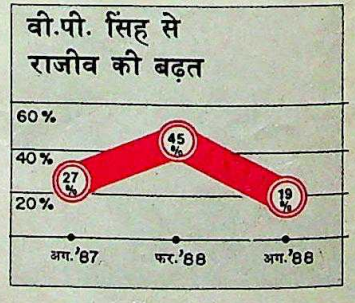

कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा?

		राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव गांधी	रामकृष्ण हेगड़े	राजीव गांधी	ज्योति बसु
उत्तर		41	50	65	27	65	28
दक्षिण		70	24	66	26	69	25
पूर्व		56	37	67	28	39	58
पश्चिम		55	38	68	27	76	18
अखिल भारतीय	अग. 88	56	37	67	27	60	35
	फर. 88	68	23	75	18	68	26
	अग. 87	61	34	66	30	70	27
इंका के वोटर		82	12	90	6	84	12
विपक्ष के वोटर		36	56	49	43	42	52

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गृहणी को उत्तम उपहार

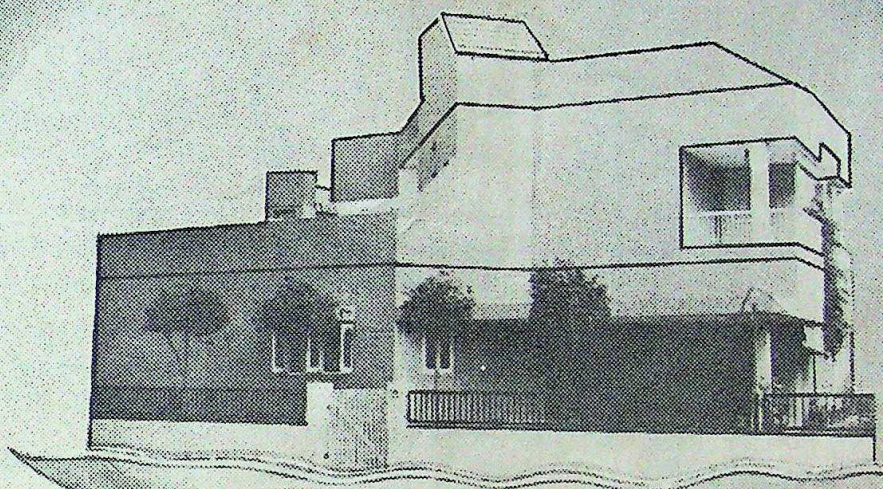

सुन्दर सुदृढ़ निर्माण का आधार

जे. के. सीमेंट

से हो साकार

अगर अपना घर बनाएं, जे. के. सीमेंट ही लगाएं..

जे. के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा (राज.)

JAYKAY

ASHOKA

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वोत्तम 'वैकल्पिक' प्रधानमंत्री

	रामकृष्ण हेगड़े	चंद्रशेखर	वी.पी. सिंह	अजीत सिंह	एन.टी. रामराव
उत्तर	3	9	79	3	6
दक्षिण	23	6	42	2	27
पूर्व	8	8	73	2	9
पश्चिम	9	11	61	2	16
अखिल भारतीय	**11**	**9**	**63**	**2**	**15**

('पता नहीं' शामिल नहीं, शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है)

(सभी आकड़े प्रतिशत में)

वी.पी. सिंह सर्वोत्तम विकल्प

मतदाताओं को पांच विपक्षी नेताओं के नाम दिए गए और उनसे पूछा गया कि कौन सर्वोत्तम प्रधानमंत्री साबित होगा. समूचे देश में मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से वी.पी. सिंह को सर्वोत्तम माना. दक्षिण को छोड़कर उन्हें सभी क्षेत्रों में पूर्ण बहुमत मिला. दक्षिण में भी वे वहां के क्षेत्रीय नेताओं—नंदमूरि तारक रामराव और रामकृष्ण हेगड़े से आगे हैं. यह बात महत्वपूर्ण है कि हिंदीभाषी इलाकों में भी चंद्रशेखर और अजीत सिंह को बहुत ही कम समर्थन मिला.

विपक्षी एकता पर संदेह

जनमत संग्रह से पता चलता है कि विपक्ष यदि 1977 की तरह एकजुट हो गया तो इंका को आम चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी. इसके लिए प्रायः हर चुनाव क्षेत्र में एक ही विपक्षी उम्मीदवार को चुनाव लड़ना होगा. लेकिन 1977 के अनुभव से मतदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है—क्या विपक्ष एक रह पाएगा?

विपक्षी नेताओं की अनेक बैठकें हो रही हैं और हरियाणा के धुरंधर देवीलाल समाजवादी जनता दल में अपने सहयोगियों को पद बांट रहे हैं, फिर भी अधिकांश मतदाताओं का मानना है कि यह नवगठित दल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा. (जनमत संग्रह कराने के समय तक सात पार्टियों का राष्ट्रीय मोर्चा नहीं बना था इसलिए नतीजों की गणना में इस घटना को मद्देनजर नहीं रखा गया है).

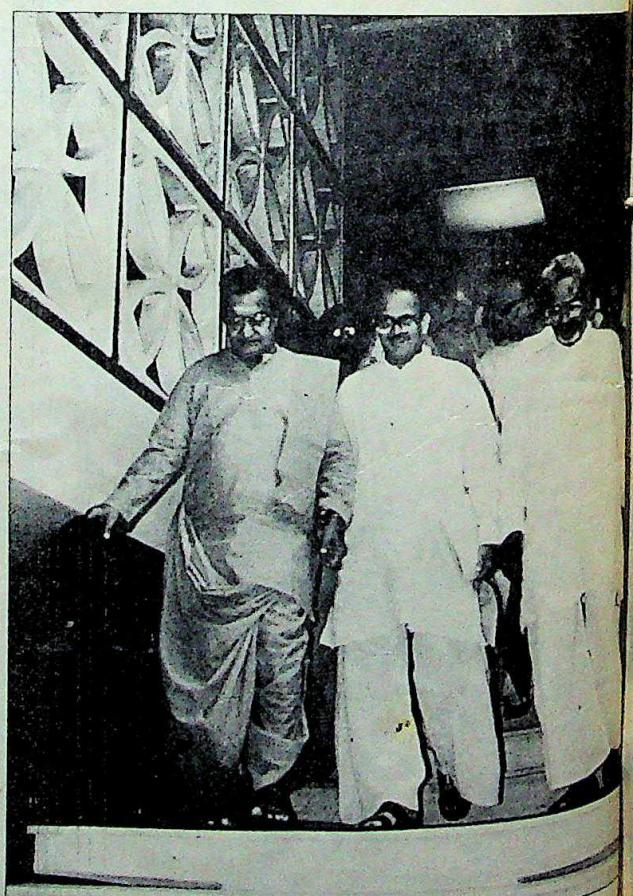

एक रहेंगे या टूटेंगे?

	टूटेंगे	एक रहेंगे
उत्तर	62	38
दक्षिण	63	37
पूर्व	73	27
पश्चिम	64	36
अखिल भारतीय	**65**	**35**

('पता नहीं' शामिल नहीं)

(सभी आकड़े प्रतिशत में)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वी.पी. सिंह ने फासला कम किया

जनमत संग्रह में राजीव और वी.पी. सिंह के बीच अनेक मुद्दों पर तुलनात्मक राय जानने की कोशिश की गई. वी.पी. सिंह ने अपने मुकाबले प्रधानमंत्री की बढ़त तेजी से घटा दी है. वैसे अभी भी राजीव गांधी

- ज्यादा ईमानदार
- बेहतर प्रशासक
- ज्यादा स्पष्ट नजरिये वाले
- ज्यादा गरीब समर्थक

माने जा रहे हैं. लेकिन इन मामलों में वी.पी. सिंह के मुकाबले उनकी बढ़त घटी है.

जहां तक प्रधानमंत्री पद पर दावे की बात है, उत्तरी भारत में वी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री का तख्ता पलट दिया है. यहां उन्हें हर दृष्टि से राजीव से बेहतर माना गया है. दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने फासला कम किया है.

जहां इंका के मतदाता अभी भी पूरी तरह राजीव के साथ हैं, वहीं विपक्षी मतदाताओं के बीच उनकी स्थिति खराब हुई है. फरवरी 1988 के जनमत संग्रह में विपक्षी मतदाताओं में भी राजीव को ज्यादा गरीब समर्थक और बेहतर दृष्टि वाला माना गया था. वी.पी. सिंह को ज्यादा ईमानदार माना गया था. लेकिन इस संग्रह में वी.पी. सिंह ने विपक्षी मतदाताओं के बीच हर मामले में बढ़त हासिल कर ली है.

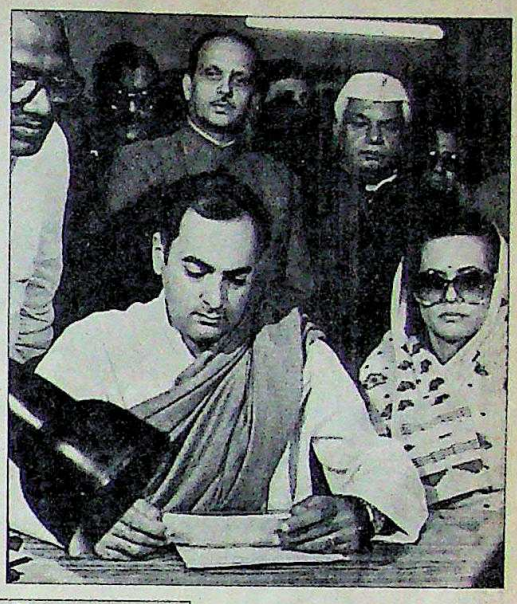

राजीव गांधी बनाम वी.पी. सिंह

अधिक ईमानदार

		राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर		32	52	– 20
दक्षिण		68	26	+ 42
पूर्व		47	42	+ 5
पश्चिम		53	36	+ 23
अखिल भारतीय	अग. 88	50	39	+ 11
	फर. 88	62	25	+ 37
इंका के वोटर		75	15	+ 60
विपक्ष के वोटर		32	56	– 24

('पता नहीं' शामिल नहीं, शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

बेहतर प्रशासक

		राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर		41	50	– 9
दक्षिण		70	25	+ 45
पूर्व		55	38	+ 17
पश्चिम		58	34	+ 24
अखिल भारतीय	अग. 88	57	36	+ 21
	फर. 88	68	23	+ 45
इंका के वोटर		82	13	+ 69
विपक्ष के वोटर		38	54	– 16

('पता नहीं' शामिल नहीं, शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

ज्यादा स्पष्ट नजरिया

		राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर		40	51	– 11
दक्षिण		70	25	+ 45
पूर्व		54	39	+ 16
पश्चिम		59	34	+ 25
अखिल भारतीय	अग. 88	56	37	+ 19
	फर. 88	68	22	+ 46
इंका के वोटर		81	13	+ 68
विपक्ष के वोटर		38	54	– 16

('पता नहीं' शामिल नहीं, शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

अधिक गरीब समर्थक

		राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर		42	45	– 3
दक्षिण		71	23	+ 48
पूर्व		49	37	+ 12
पश्चिम		61	30	+ 29
अखिल भारतीय	अग. 88	57	33	+ 24
	फर. 88	70	18	+ 52
इंका के वोटर		81	11	+ 70
विपक्ष के वोटर		38	51	– 13

('पता नहीं' शामिल नहीं, शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रधानमंत्री की नीतियां

		गरीब समर्थक	अमीर समर्थक	दोनों नहीं
उत्तर		37	47	16
दक्षिण		48	32	20
पूर्व		24	50	26
पश्चिम		53	35	12
अखिल भारतीय	अग. 88	41	40	19
	फर. 88	55	33	12
इंका के वोटर		59	21	20
विपक्ष के वोटर		28	55	17

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

उत्तर और दक्षिण का अंतर

जनमत संग्रह में एक ऐसा सवाल भी पूछा गया जिसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा. सवाल था कि पिछले जनमत संग्रह के बाद के छह महीनों में प्रधानमंत्री को वी.पी. सिंह की चुनौती ज्यादा मजबूत हो गई है, कमजोर हुई या जस की तस है. इस जून में इलाहाबाद उपचुनाव में वी.पी. सिंह की भारी विजय के बाद यह सवाल ज्यादा पेचीदा हो उठा था.

बहुमत की राय थी (खासकर उत्तर में) कि छह महीने पहले की तुलना में आज वी.पी. सिंह राजीव को ज्यादा तगड़ी चुनौती दे रहे हैं. तीनों जनमत संग्रहों में दक्षिण में वी.पी. सिंह को ज्यादा समर्थन नहीं मिला और अब वहां के अधिकांश मतदाताओं का मानना है कि उनकी चुनौती कमजोर हुई है. वहां ऐसा मानने वाले 56 फीसदी हैं.

राजीव की गरीब समर्थक छवि बिगड़ी

प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है यह बात एक और तथ्य से प्रमाणित होती है. उनकी नीतियां गरीब समर्थक हैं या अमीर समर्थक, इस पर जनमत बंटा हुआ है. फरवरी '88 में 55 फीसदी लोगों को उनकी नीतियां गरीब समर्थक लगती थीं. अब यह संख्या 41 फीसदी हो गई है. फरवरी '88 में इंका को वोट देने वाले 72 फीसदी लोग उनकी नीतियों को गरीब समर्थक मानते थे, अब यह तादाद 59 फीसदी ही रह गई है. इसी तरह विपक्ष को वोट देने वालों में भी राजीव की गरीब समर्थक छवि बिगड़ी है.

क्या वी.पी. सिंह की स्थिति मजबूत हुई है?

	मजबूत हुई	वैसी ही है	कमजोर हुई
उत्तर	65	26	9
दक्षिण	42	2	56
पूर्व	55	26	19
पश्चिम	51	30	19
अखिल भारतीय	53	23	24

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

इलाहाबाद की जीत की कम जानकारी

वैसे विपक्षी दलों और पत्र-पत्रिकाओं के एक समूह ने वी.पी. सिंह को अगला प्रधानमंत्री भले ही बना दिया हो लेकिन जनमत संग्रह में हिस्सा लेने वाले 64 फीसदी लोगों को पता ही नहीं कि इलाहाबाद उपचुनाव में उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल की है. शहरी और पुरुष मतदाताओं के आधे हिस्से को जीत की खबर है लेकिन सिर्फ 18 फीसदी महिलाओं और 26 फीसदी ग्रामीणों को ही इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद उपचुनाव वी.पी. सिंह ने जीत लिया है.

	पता है	पता नहीं
मर्द	49	51
औरतें	18	82

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

इलाहाबाद की जीत की जानकारी

	ग्रामीण		शहरी		कुल	
	पता है	पता नहीं	पता है	पता नहीं	पता है	पता नहीं
उत्तर	28	72	54	46	47	53
दक्षिण	18	82	28	72	24	76
पूर्व	30	70	64	36	39	61
पश्चिम	27	73	54	46	36	64
कुल	26	74	51	49	36	64

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

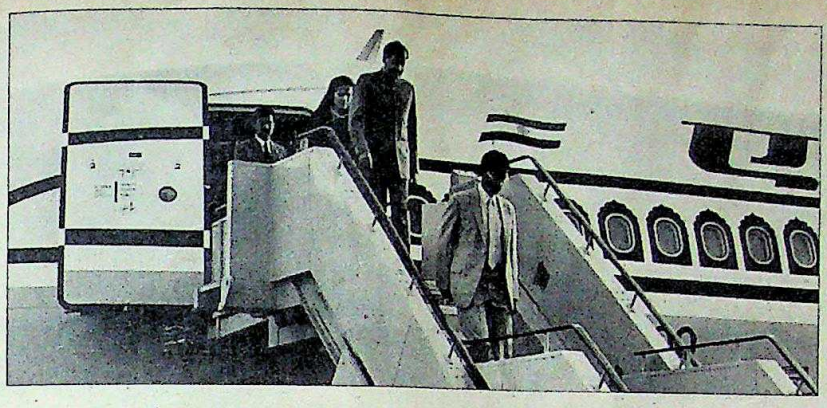

जनमोर्चा की पहचान बढ़ी

अखबारों-पत्रकारों में जबरदस्त चर्चा के बावजूद सिर्फ एक तिहाई मतदाताओं ने ही जनमोर्चा का नाम सुना है. वैसे फरवरी 1988 में तो सिर्फ 21 फीसदी को ही यह जानकारी थी. जागरूकता का स्तर बढ़ना महत्वपूर्ण तो है लेकिन यह बहुत कम है.

राजीव की विदेश यात्राओं पर सहमति

प्रधानमंत्री की धारावाहिक विदेश यात्राओं की काफी आलोचना हुई है. लेकिन ज्यादा मतदाताओं को लगता है कि ऐसी यात्राओं से देश को फायदा होता है. दक्षिण के ज्यादा मतदाताओं ने ऐसी राय दी, जबकि उत्तर के ज्यादा मतदाता इसके खिलाफ हैं.

जनमोर्चा का नाम सुना है

		हां	नहीं
उत्तर		40	60
दक्षिण		26	74
पूर्व		36	64
पश्चिम		37	63
अखिल भारतीय	अग. 88	34	66
	फर. 88	21	79

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं

	देश के लिए अच्छी	जनता के पैसे की बरबादी
उत्तर	46	54
दक्षिण	71	29
पूर्व	59	41
पश्चिम	58	42
अखिल भारतीय	60	40

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

निजी और राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई ही मुख्य समस्या

महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है. भ्रष्टाचार का नंबर इसके बाद आता है. वैसे महिलाओं ने महंगाई को मुख्य समस्या माना तो पुरुषों ने भ्रष्टाचार का ज्यादा जिक्र किया. 14 फीसदी लोगों ने सांप्रदायिकता को मुख्य समस्या माना, जिनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है.

निजी स्तर पर भी लोगों—खासकर महिलाओं—ने आज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में महंगाई का ही जिक्र किया. महिलाओं में यह में यह आंकड़ा यदि 53 प्रतिशत था तो पुरुषों में 42 प्रतिशत. दूसरी सबसे बड़ी समस्या—बेरोजगारी—का उल्लेख महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने ज्यादा किया.

देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे

अखिल भारतीय	महंगाई	भ्रष्टाचार	सांप्रदायिकता	कानून और व्यवस्था
अगस्त '88	46	35	14	5
फरवरी '88	48	34	12	6
अगस्त '87	32	36	23	9
मर्द (अग. '88)	36	39	18	7
औरतें (अग. '88)	61	27	9	3

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

निजी स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दे

अखिल भारतीय	महंगाई	बेरोजगारी	पानी	बिजली
अगस्त '88	46	31	15	8
फरवरी '88	48	29	16	7
अगस्त '87	36	34	21	9
मर्द (अग. '88)	42	34	15	9
औरतें (अग. '88)	53	24	15	8

('पता नहीं' शामिल नहीं) (सभी आकड़े प्रतिशत में)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रशांत पंजियार

इस्तीफे की घोषणा करते हेगड़े: मलिन छवि

कर्नाटक

मूल्यों की महंगी कीमत

फोन कांड की वजह से हेगड़े का इस्तीफा, बोम्मई नए मुख्यमंत्री

करीब चार साल से राजीव गांधी और उनकी सरकार राजनीति के इस दुरूह खेल में नौसिखुए खिलाड़ी होने का ठप्पा झेलती आ रही थी. लेकिन पिछले पखवाड़े, जब संसद में सरकार की जान सांसत में थी, उसने अपनी पहली राजनैतिक तुरुप चाल चली. अचानक, थोड़े वक्त के लिए ही सही, बोफोर्स और सूरी बंधुओं के मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गए और साफ-सुथरे माने जाने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े चर्चा का केंद्र बन गए. एक दिन पहले तक ही वे विपक्ष के चमकते सितारे थे. उनके पांच वर्षीय शासन का बदनामी भरा अंत तो हुआ ही, उन्हें शर्मिंदगी अलग उठानी पड़ी. वैसे उनके भरोसेमंद एस.आर. बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने से कुछ क्षतिपूर्ति तो हुई लेकिन दाग तो लग ही गया.

दिल्ली में इस्तीफे की घोषणा के बाद हेगड़े ने बहादुरी जताते हुए कहा, "मैं राजीव गांधी सरीखा नहीं हूं जो इससे भी ज्यादा गंभीर भंडाफोड़ों के बावजूद गद्दी पर बने हुए हैं." लेकिन उनकी आंखें दर्द, शर्मिंदगी और कुछ हद तक पश्चाताप के भाव चाहते हुए भी छुपा नहीं पा रही थीं.

हताश हेगड़े के बंगलूर रवाना होने के साथ ही उनकी पार्टी के दोनों धड़ों में रणभेरी बज उठी. पिछली बार इस्तीफे की धमकी से वे सहानुभूति के पात्र बने थे पर इस बार उनके सबसे ज्यादा वफादार दोस्तों ने भी उनका बचाव करने में दिक्कत महसूस की. उनमें से एक ने कहा, "दूसरों के टेलीफोन सुनना तो बहुत विस्मयजनक बात है, खासकर इसलिए कि टेलीफोन विभाग आखिर केंद्र के अधीन है."

भवान सिंह

बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने से कर्नाटक की राजनीति पर हेगड़े का कब्जा बना रहा

इसी बात का फायदा उठाकर केंद्र ने हेगड़े का पांसा पलट दिया. विडंबना यह है कि उसने पहला सांघातिक प्रहार विपक्षी सांसदों को ही करने दिया. जनता पार्टी के मधु दंडवते और तेलुगु देशम के सी. माधव रेड्डी ने संसद में "राजनैतिक नेताओं की टेलीफोन वार्ताएं बीच में" सुने जाने के बारे में तारांकित प्रश्न पूछा था. उनका मकसद साफ था कि इससे संबंधित दूसरे सवाल उठाकर वे सत्तारूढ़ दल को सांसत में डाल देंगे.

लेकिन सरकार पहले ही तैयार बैठी थी. उसने गुप्तचर ब्यूरो को कर्नाटक में राजनीतिकों के टेलीफोन सुने जाने संबंधी मामले की जानकारी जुटाने में लगा दिया था. संचार मंत्रालय द्वारा इस मामले में रुचि लेने की वजह से जल्द ही कर्नाटक पुलिस उपमहानिदेशक के दस्तखतों वाले नौ आदेश उसके हाथ लग गए जिसमें कम-से-कम 50 असंतुष्ट जनता नेताओं और हेगड़े के राजनैतिक विरोधियों के टेलीफोन सुनने को कहा गया था. केंद्रीय संचारमंत्री बीरबहादुर सिंह ने एक पखवाड़े में ही अपनी कोशिशों के नतीजे संसद के सामने रख दिए.

इस जीत पर बीरबहादुर ने अपनी पीठ ठोंकी "जनता सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है लेकिन वह अपने अधिकारों का भारी दुरुपयोग करती आई है. हेगड़े ने तो अपने दल के सदस्यों और मंत्रियों से भी असामाजिक तत्वों जैसा व्यवहार किया क्योंकि कानून में ऐसे ही तत्वों के टेलीफोन बीच में सुनने का प्रावधान है."

अमूमन गोपनीय रखी जाने वाली सूचनाओं को जाहिर करने का बेमिसाल फैसला गृहमंत्री और संचारमंत्री की बातचीत के बाद तय हुआ. प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलते ही दोनों ने सलाह-मशविरा किया. ललित सूरी के मामले से उठे बवंडर से उबरने के लिए राजीव का यह जवाबी हमला था.

संसद में उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि राज्य सरकार ने शायद कानून का उल्लंघन किया है और वे चाहेंगे कि मामले पर गौर हो. डाक सेंसरशिप विधेयक पारित कराने के लिए राष्ट्रपति पर जोर देने की अपनी पार्टी की कोशिशें वे शायद उस समय भूल गए.

इस बात की भी अनदेखी कर दी गई कि तकरीबन हर राज्य सरकार और यहां तक कि दिल्ली में केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां भी फोन बीच में सुनने के तरीके इस्तेमाल करती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रामकृष्ण हेगड़े

'मुझे कुछ पता न था'

*नई दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद रामकृष्ण हेगड़े ने फीचर संपादक **शेखर गुप्ता** से अपने इस्तीफे की वजह और भविष्य की संभावनाओं पर बेलाग बातचीत की. विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह और पार्टी सहयोगियों—बीजू पटनायक और मधु दंडवते के टेलीफोन कॉलों के व्यवधान के बीच हुई बातचीत के अंश:*

● ***इस बार आखिर आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा:***

मुझे पूरी दृढ़ता से फैसला करना था. आप हर समय भेड़िया आया, भेड़िया आया की गुहार लगाते नहीं रह सकते. मैं जानता हूं कि मैंने कोई गलत या नाजायज काम नहीं किया. मैंने नैतिक जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा दिया है.

● ***क्या आपने टेलीफोन टेप करने का आदेश दिया था:***

नहीं, कभी नहीं. मैं तो इसके बारे में जानता तक नहीं. गुप्तचर रिपोर्टों का संक्षिप्त ब्यौरा ही मेरे पास आता था. पर उनमें सूत्र का जिक्र नहीं होता था. खुफिया विभाग वाले हर तरह के तरीके अपनाते हैं. मसलन पैसे लेकर सूचनाएं देने वाले उनके सूत्र इंका में भी हो सकते हैं. मुझे तो इस बात की भनक तक न थी कि वे टेलीफोन टेप कर रहे थे.

● ***राजीव के आरोप पर कि आपकी सरकार ने कानून तोड़ा:***

राजीव सरकार हमेशा यही करती आई है. दरअसल आदेश वे कानून के तहत भी जारी नहीं करते. मुझे पता है कि ऐसा दूरसंवेदी उपकरण लाया गया है जिसकी मदद से वे टेलीफोन टेप किए बिना ही लोगों की बातचीत सुन सकते हैं. मैं जानता हूं देश के राष्ट्रपति तक का टेलीफोन टेप किया जाता है.

● ***भंडाफोड़ की जिम्मेदारी किसकी:***

यह सब हमारी अपनी ही पार्टी के लोगों के कारण हुआ. इस साजिश में यहां कुछ सांसद सरकार का हाथ बंटाते रहे. मैं उनके नाम गिनाऊं, यह ठीक नहीं होगा. हर शख्स जानता है वे कौन हैं.

है. दरअसल दंडवते और रेड्डी ने अपने सवाल में कर्नाटक का जिक्र तक नहीं किया था. उन्होंने देशभर में राजनीतिकों के टेलीफोन सुने जाने का मामला उठाया था. लेकिन सरकार ने कर्नाटक को ही चर्चा के लिए चुना. इसके पहले सरकार का ऐसे सवालों के प्रति हमेशा एक ही जवाब रहा है कि सार्वजनिक हित में तथ्य जाहिर नहीं किए जा सकते. लेकिन इस बार अचानक पार्टी हित सर्वोपरि हो गए. हेगड़े की शिकायत थी, "इस पूरे मामले में जिस तरीके से सूचनाएं प्रदान की गई और उनके लिए जो वक्त चुना गया, उससे षडयंत्र की बू आती है."

मगर उनकी शिकायतें सरकार तक ही सीमित नहीं हैं. 'इंडिया टुडे' के साथ बातचीत में (देखें साक्षात्कार) उन्होंने बार-बार दुहराया कि उनकी पार्टी के लोगों ने ही उनसे दगा की वे कहते हैं, "उनका केंद्र से बराबर संपर्क बना रहा. वे ही इसके जिम्मेवार हैं."

एक तरह से, दिल्ली और बंगलूर में उनकी पार्टी के भीतर मना के लिए हो रही उठापटक का यही तार्किक अंत था. यह बात छुपी नहीं है कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष अजीत सिंह और चंद्रशेखर हेगड़े की क्षमताओं से ईर्ष्या करते हैं. असंतुष्ट नेता देवगौड़ा बंगलूर में उनके मोहरे रहे हैं. इस सारी मुसीबत की शुरुआत देवगौड़ा और अजीत सिंह की षडयंत्रकारी बातचीत से ही हुई थी. बात टेप होने के बाद 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुखपृष्ठ तक पहुंच गई और यहीं से बवाल शुरू हुआ.

हेगड़े के इस्तीफे से बंगलूर में उनके समर्थक निराश, तो असंतुष्ट खुश थे. शायद इसी माहौल का फायदा लेने के लिए देवगौड़ा को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर दिखाया गया. लेकिन 12 अगस्त को हेगड़े के खेमे के और उनके विश्वासपात्र मंत्री एस.आर. बोम्मई को सर्वसम्मति से नया मुख्यमंत्री चुने जाने से राज्य की राजनीति पर हेगड़े का कब्जा बरकरार ही रहा. मजे की बात है कि बोम्मई के नाम का प्रस्ताव देवगौड़ा ने ही किया.

कर्नाटक से हेगड़े विदाई से की सरगर्मी दिल्ली में शुरू हो गई है. राजनैतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि विपक्षी एकता की सामूहिक कोशिशों पर इसका क्या असर पड़ेगा. हेगड़े ने खुद ही सारे शको-शुबहे मिटाते हुए कहा, "मैं नहीं समझता इससे कोई ज्यादा नुकसान होगा. मैंने सही कदम उठाया है." इस्तीफे की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद वी.पी. सिंह ने टालमटोल के अंदाज में कहा, "उन्होंने सैद्धांतिक रुख अपनाया है. इससे लोगों की नजर में निश्चय ही उनकी इज्जत बढ़ेगी. लेकिन विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता."

हेगड़े की चतुराई भी उन्हें इससे पहुंचा आघात छुपा नहीं पाई. वे नवगठित समाजवादी जनता दल के उपाध्यक्ष हैं और उसके मुख्य स्तंभ भी. साख फिर से स्थापित करने के लिए उन्हें अब भारी मशक्कत करनी पड़ेगी. पखवाड़ा बीतते-बीतते वरिष्ठ विपक्षी नेता संभावित नुकसान को रोकने के लिए विचार-विमर्श में जुटे हुए थे. इनमें से एक नेता ने माना, "इसका एहसास ही भयानक है. हमने तो इस बारे में कभी सोचा तक नहीं था."

लेकिन जो भी हो, एक बात निश्चित है. बंगलूर में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से हेगड़े की दिल्ली आने और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में शामिल होने की मुराद आखिर पूरी तो हो गई. यह बात दीगर हैं कि वे ऐसे मजबूर होकर आना चाहते थे या नहीं.

—शेखर गुप्ता और प्रभु चावला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: प्रशांत पंडित्या

विपक्ष

बंधी मुट्ठी लाख की

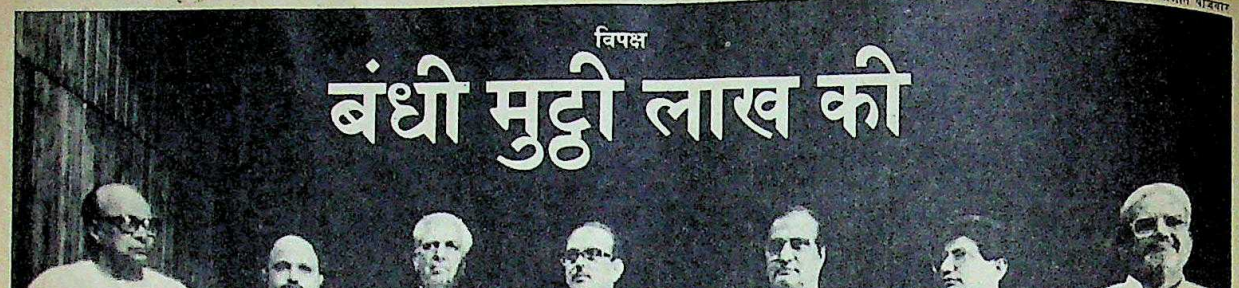

विपक्षी एकता के दूसरे अंक का पहला दृश्य शुरू होता है. (पहला अंक पिछले महीने खेला गया था जिसके नायक थे हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल). इस बार परदा उठते ही मंच पर विराजमान हैं असली फिल्मी नायक यानी आंध्र के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव. देश की राजधानी में यह मंच सजा है आंध्र भवन में, जहां विपक्ष के दिग्गज अपनी-अपनी भूमिका निभाने आ पहुंचे हैं. इतिहास बनाने की अपनी भूमिका के प्रति पूरी तरह सचेत रामराव हर क्षण महान व्यक्ति जैसा अभिनय करते हैं. उनके लंबे-चौड़े भाषण का एक ही सार है—एक हो जाओ या तबाही के लिए तैयार रहो.

और आखिरकार दो दिन तक परदे के पीछे चली जोड़-तोड़, मान-मनौवल और तीन घंटे की नौटंकी के बाद राष्ट्रीय हैसियत पाने का रामराव का बरसों पुराना सपना साकार होता लगता है. छह साल पुरानी क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ उन्हें नए बने सात पार्टियों के राष्ट्रीय मोर्चे का ताज भी पहना दिया गया. विश्वनाथ प्रताप सिंह को मोर्चे का संयोजक बनाया गया.

मोर्चे का घटक बनने के लिए सहमत पार्टियों में जनता पार्टी, तेलुगु देशम, कांग्रेस (स), द्रविड मुनेत्र कडगम (द्रमुक), असम गण परिषद, लोकदल और जनमोर्चा शामिल हैं.

इस पूरे तामझाम पर हर तरह से रामराव की छाप थी. उन्होंने साबित कर दिखाया कि वे राजनैतिक तौर पर किसी भी मायने में देवीलाल से उन्नीस नहीं हैं. देवीलाल ने पिछले महीने जनता पार्टी, कांग्रेस (स), लोकदल और जनमोर्चा का जोड़-तोड़ बिठाकर समाजवादी जनता दल (सजद) बनवा दिया था. कुल मिलाकर रामराव का मिशन था—भाजपा के अलावा सभी मध्यमार्गी दलों को अपनी अगुआई में इकट्ठा करना और उत्तर भारत के निर्विवाद नेता के तौर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को स्थापित करना.

इसी के मद्देनजर उन्होंने जता दिया था कि अगर इस बार एकता की कोशिशें नाकाम रहीं तो वे आगे कभी एकता वार्ताओं में शामिल नहीं होंगे. यह रामराव के बस की ही बात थी कि उन्होंने द्रमुक नेता करुणानिधि को चार साल बाद दिल्ली आने के लिए मना लिया. उन्होंने आखिरी दौर की बातचीत में असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत को भी शामिल होने के लिए राजी कर लिया.

चार अगस्त को दिल्ली पहुंचते ही रामराव अपने काम में जुट गए. अगले 24 घंटे उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह, कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, जपा नेता चंद्रशेखर, लोकदल अध्यक्ष हेमवतीनंदन बहुगुणा तथा भाजपा नेताओं—लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अलग-अलग विचार-विमर्श में गुजारे. अगले दिन जब सारे नेता आखिरी बातचीत के लिए जुटे तो स्पष्ट था कि रामराव की इच्छा ही सर्वोपरि रही है. न सिर्फ पहले की सभी एकता वार्ताओं से अलग रहे बहुगुणा और

गठन के बाद सात दलीय मोर्चे के नेता

चंद्रशेखर वहां मौजूद थे बल्कि रामराव ने मोर्चे के पदाधिकारियों की सूची पर भी विभिन्न नेताओं की सहमति ले ली थी.

विभिन्न समितियां बनाने और पदाधिकारियों के चयन में रामराव यह संकेत दे रहे लगते थे कि वे बहुगुणा और चंद्रशेखर जैसे विघ्नसंतोषियों को महत्वपूर्ण पदों से दूर रखने की ठाने हुए हैं. इस तरह वे फैसले लेने की प्रक्रिया में उनका प्रभाव कम करना चाहते थे. उन्होंने देवीलाल के साथ मिलकर जो फार्मूला तैयार किया उसके अनुसार ऐसे लोगों को ही मोर्चे के अध्यक्ष मंडल जैसी असरदार समितियों में शामिल किया गया जो एकता प्रयास के प्रबल समर्थक थे और वी.पी. सिंह के साथ-साथ खुद उनका नेतृत्व मानने को तैयार थे.

यह फैसला भी हुआ कि सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों और पार्टी अध्यक्षों को 11 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल में रखा जाए. यही समिति महत्वपूर्ण फैसले लेगी. इस फार्मूले के तहत बहुगुणा को लोकदल अध्यक्ष होने के नाते हालांकि अध्यक्ष मंडल में जगह देनी पड़ी पर वहां उनकी कोई ज्यादा हैसियत नहीं होगी. उनके 10 विरोधी भी तो होंगे ही.

बहुगुणा और जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे परेशानी खड़े करने वाले लोगों को मोर्चे की आठ सदस्यीय कार्रवाई समिति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में रखा गया. यही समिति मोर्चे का अमली कार्यक्रम चलाएगी. करुणानिधि कहते हैं, "दक्षिण से उत्तर तक की पार्टियां एक परचम तले एक ही मंच पर इकट्ठा होने से देश की अब तक की सबसे मजबूत विपक्षी ताकत खड़ी हो जाएगी."

लेकिन मोर्चे का हाल ही में जारी 31 सूत्री कार्यक्रम चूं-चूं का मुरब्बा लगता है इसमें समाजवादी लटके-झटके हैं, तो वेमतलब शब्दावली भी ठुंसी पड़ी है. यहां तक कि दकियानूसी मुहावरों की भी इसमें भरमार है. मसलन, मोर्चा करों के प्रति 'उचित और तर्कसंगत रवैया अपनाएगा'; मशीनों का इस्तेमाल सीमित करेगा ताकि वे इंसानी मेहनत की जगह न ले लें'; अनुसूचित जाति के लोगों को 'बौद्ध बनने के बाद भी' रियायतें देगा; श्रमिक बहुलता वाले उद्योगों को तरजीह देगा.

भारतीय युवा इंका अध्यक्ष मुकुल वासनिक कहते हैं, "यह मोर्चा महज उन कुंठित विपक्षी नेताओं का मौकापरस्त गठजोड़ है जो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं." सचमुच यह संभावना है कि मोर्चे को पहली चुनौती इंका से नहीं बल्कि शायद अपने ही घटकों से मिले. ये सभी घटक पिछले पखवाड़े एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हुए थे. राष्ट्रीय मोर्चे के संविधान की औपचारिक घोषणा हो ही रही थी कि नवगठित समाजवादी जनता दल में दरारें दिखने लगीं. मजे की बात है कि मोर्चे में एक ही घटक के तौर पर दल का जिक्र तक नहीं है. बल्कि उसमें विलीन होने वाली चारों पार्टियां अपने अलग-अलग अस्तित्व और पहचान के साथ ही मोर्चे में शामिल हुई हैं.

दल के प्रमुख शिल्पकार देवीलाल ने जब पार्टी के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की थी तो जैसे तूफान बरपा हो गया. उन्होंने वी.पी. सिंह को समाजवादी जनता दल का अध्यक्ष, हेगड़े को उपाध्यक्ष और अजीत सिंह को प्रमुख महासचिव घोषित किया था. खुद अपने लिए उन्होंने संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता सुरक्षित रखी और मधु दंडवते को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बना दिया. मगर इसके तुरंत बाद ही लगभग हर घटक पार्टी ने अपने विरोध का इजहार किया.

जैसी कि उम्मीद थी, सबसे जोरदार विरोध जनता पार्टी के चंद्रशेखर समर्थकों ने किया. चंद्रशेखर के खासमखास और पार्टी के उपाध्यक्ष इंदुभाई पटेल सहित पूर्व महासचिव यशवंत सिन्हा ने सबसे पहले समाजवादी जनता दल के इन नए पदाधिकारियों के चयन की भर्त्सना की. पटेल ने कहा, "जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे राजनैतिक आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे." उधर कांग्रेस (स) के नेता के.पी. उन्नीकृष्णन ने कहा, "देवीलाल जैसे वयोवृद्ध नेता ने इस तरह का गैरजिम्मेदाराना बर्ताव किया, यह वाकई हैरतअंगेज है." लेकिन देवीलाल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. उन्होंने कहा, "मैंने घोषणा करने से पहले हर महत्वपूर्ण नेता से सलाह ले ली थी. बीमारी के बावजूद मैं विपक्षी एकता के लिए जुटा रहा."

बतौर राजनैतिक पार्टी जल्द ही पंजीकृत होने वाले समाजवादी जनता दल में जनमोर्चा के विलय का मतलब चूंकि यह होता कि उसके सांसदों और विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत इस्तीफा देना पड़ता इसलिए जनमोर्चा वालों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखना ही बेहतर माना. राष्ट्रीय मोर्चे की तरह ही फ़िलहाल जनमोर्चा भी पंजीकृत राजनैतिक दल न हो कर एक साझा संगठन है इसलिए राष्ट्रीय मोर्चे अथवा जनमोर्चे में शामिल लोगों पर दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता. पर यह समाजवादी जनता दल में शामिल होने वालों पर जरूर लागू होता है.

मगर विपक्षी एकता के प्रति अपनी तत्परता सिद्ध करने के लिए वी.पी. सिंह ने धमकी दे डाली कि अगर उनके साथ कोई नहीं आता तो भी वे इलाहाबाद की सीट से इस्तीफा देकर सजद में शामिल हो जाएंगे. उनके अनुयायियों को भी उनकी यह जिद माननी पड़ी. जनमोर्चा सांसदों ने अपने इस्तीफे उन्हें सौंप दिए. लोकसभा के तेजतर्रार सदस्य आरिफ मुहम्मद खां कहते हैं, "वी.पी. सिंह विपक्षी एकता का अपना वचन पूरा कर सकें इसके लिए हम कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हैं." विपक्षी नेताओं ने संयम और लचीलापन जरूर दिखाया है पर अभी तक वे ऐसा माहौल बनाने में कामयाब नहीं हुए, जिससे उनकी इंका के एक विश्वसनीय विकल्प के तौर पर पहचान बनी हो. राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों से अपने भावी रिश्तों के बारे में हालांकि अभी स्पष्ट तय नहीं किया है पर रामराव का दावा है, "हम उनसे दूर नहीं भागेंगे. वक्त आने पर हम एक साथ होंगे." लेकिन भाजपा और कम्युनिस्टों को एक ही नाव पर लाने का वक्त आएगा तो विपक्ष की नैया में छेद उभरते नजर आएंगे.

—प्रभु चावला

एकता विरोधी माने जाने वाले चंद्रशेखर और बहुगुणा को राष्ट्रीय मोर्चे की नीति निर्धारक समितियों में जानबूझकर शामिल नहीं किया गया

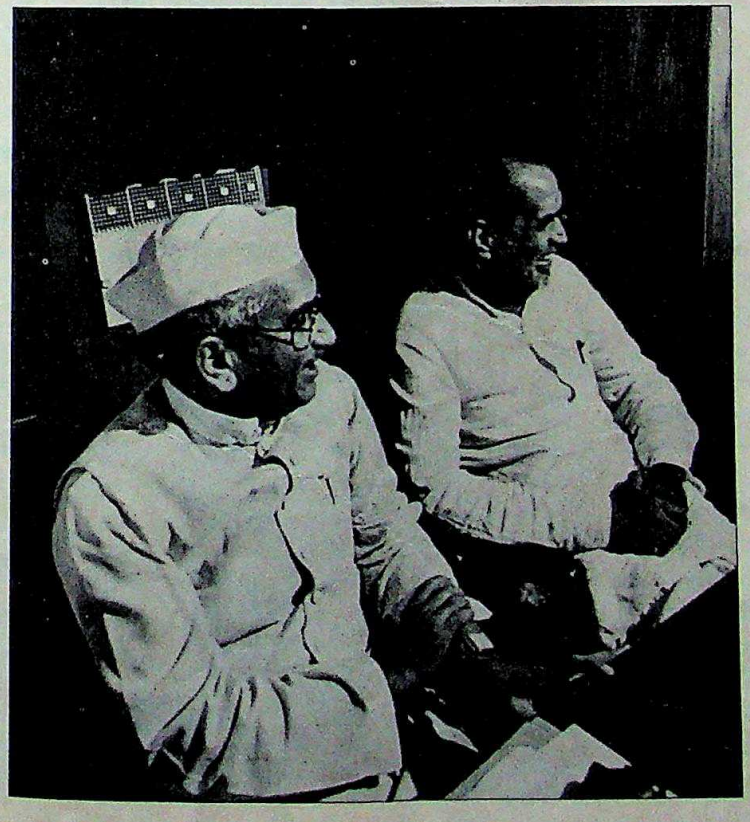

बहुगुणा (बाएं) और चंद्रशेखर: सिक्का नहीं चला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

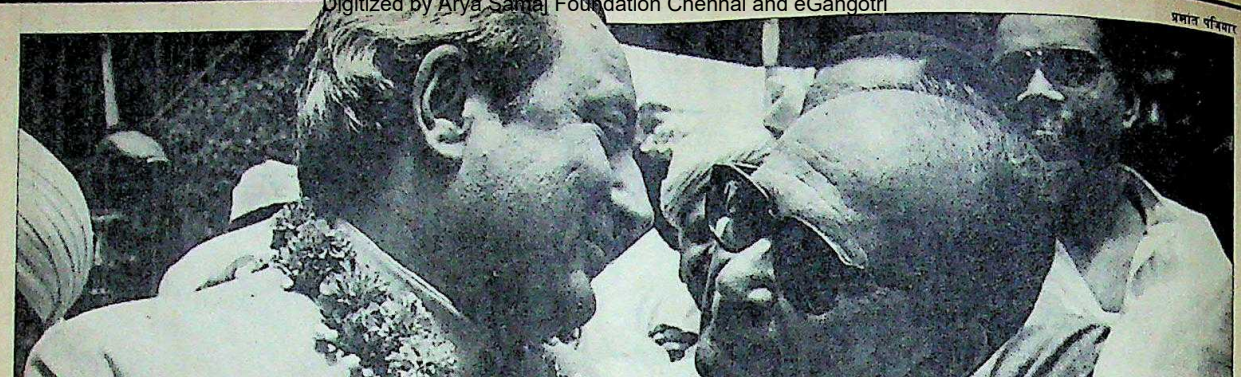

प्रभात पंजियार

दिल्ली

बेमतलब कुर्बानियां

बड़े पैमाने पर फेरबदल से भी हालत शायद ही सुधरे

महामारी ने दोतरफा मार की है. दिल्ली के यमुनापार के इलाके में पिछले पखवाड़े तक हैजे और आंत्रशोथ ने करीब 300 लोगों के प्राण लील लिए. दूसरी तरफ प्रशासन में कइयों की कुरबानी चढ़ गई. पहली बलि उपराज्यपाल हरकिशनलाल कपूर की हुई है. इसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव के.के. माथुर, निगम आयुक्त पी.पी. चौहान और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष ओम कुमार का तबादला हो गया और तीन मुख्य इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया.

इसके बाद सरकार खाली पदों को भरने की कोशिशों में जुट गई. लेकिन इन शिखर-स्थलों के लिए आदमी तलाशना इतना आसान नहीं था. यहां तक कि उपराज्यपाल के पद के साथ जुड़ा सत्ता-सम्मोहन भी इस गुरुतर दायित्व की भरपाई करने में नाकाम लगा और कुछ संभावित उम्मीदवारों ने इस पद पर आने से इनकार कर दिया.

आखिरकार 1 अगस्त को पूर्व विदेश सचिव और कांग्रेस (इ) के विदेशी मामलों के कक्ष के तत्कालीन प्रधान रोमेश भंडारी के घर 18, अकबर रोड पर फोन की घंटी घनघनाई. दूसरी तरफ राजीव थे. वे जानना चाहते थे कि क्या भंडारी उपराज्यपाल बनने को तैयार हैं. भंडारी ने हां कह दी. नियुक्ति की घोषणा दो दिन बाद तभी की गई जब गृहमंत्री बूटासिंह कोहिमा से लौट आए.

दूसरे खाली पदों पर भी विश्वासपात्र लोगों को नियुक्त किया गया. अरुणाचल प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर साल भर से कम बिताने वाले विजय कपूर को मुख्य सचिव बनाया गया.

राजधानी के लिहाज से बेहद अहम डीडीए का जिम्मा बूटा सिंह के करीबी माने जाने वाले पंजाब काडर के एक वरिष्ठ अधिकारी के.एस. बैंस को सौंपा गया. इस नियुक्ति से नौकरशाही हलके में खुसर-

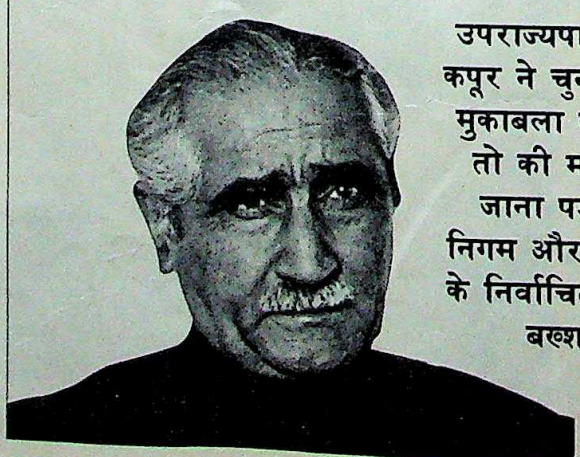

उपराज्यपाल हरकिशनलाल कपूर ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की कोशिश तो की मगर अंततः उन्हें जाना पड़ा जबकि नगर निगम और महानगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बख्श दिया गया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हार पहने भंडारी के साथ भगत

फुसर शुरू हो गई क्योंकि बैंस केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में अपना पांच साल का कार्यकाल पहले ही पूरा कर चुके हैं. वे पंजाब में नियुक्ति के इंतजार में थे. दिल्ली प्रशासन के सचिव (जमीन और निर्माण) गंगादास को निगम आयुक्त नियुक्त किया गया.

नए अफसर अपने पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो शहर प्रशासन का मनोबल काफी हद तक मंद पड़ा हुआ था. अफसरशाही बुरी तरह आक्रांत थी. अधिकारियों की टोली को जब-तब प्रधानमंत्री निवास से बुलावा आ जाता. राजीव बहुत नाराज थे, वे कोई बहानेबाजी सुनने को तैयार नहीं थे.

एक इंजीनियर से उन्होंने पूछा, "आप कौन हैं?" इंजीनियर ने अपने नाम और पद की जानकारी उन्हें दी. नाम एक पर्ची पर दर्ज किए जा रहे थे. जल्दी ही उन थके-हारे प्रशासकीय लोगों को आभास हो गया कि उनकी छुट्टी होने वाली है. उसी दिन दूरदर्शन के समाचार बुलेटिन में इसकी घोषणा भी कर दी गई. लेकिन इससे राजीव की चलताऊ किस्म की प्रशासकीय शैली के बारे में मौलिक सवाल भी उभरे.

मुअत्तल इंजीनियरों में से एक डी.आर. शर्मा ने तो सिर्फ एक हफ्ते पहले ही सफाई महकमे का कार्यभार संभाला था. महामारी फैलते ही नगर निगम ने 19 जुलाई को उन्हें खासकर सफाई के काम की देखरेख करने के लिए जल-मल निकास निदेशक के रूप में नियुक्त किया था. अवकाश ग्रहण में मात्र नौ महीने बाकी रहने के कारण शर्मा इस चुनौती को हाथ में लेने से हिचक रहे थे. आखिरकार 22 जुलाई को उन्हें पद स्वीकार करने के लिए मना लिया गया. उसी दिन राजीव ने कुछ पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया और तुरतफुरत कार्रवाई की मांग की. पिछले पखवाड़े शर्मा काफी खिन्न थे. उन्होंने कहा कि महापौर महिंदर सिंह साथी और स्थायी समिति के अध्यक्ष दीपचंद बंधु ने भी उनसे यह पद संभालने का आग्रह किया था. उनका कहना है कि जिस हफ्ते उन्होंने कार्य संभाला उस समय उन लोगों ने उनके काम की लगातार प्रंशसा की. पर जब राजीव के गुस्से का सामना हुआ तो डर के मारे लोगों ने चुपचाप किनारा कर लिया.

यह सच है कि राजधानी में लापरवाही के कारण महामारी फैली और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए. लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने असली दोषियों को सजा दी या महज बलि के बकरे ढूंढ़ लिए? दिल्ली में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रशासकीय एजेंसियों की अधिकता के कारण उपराज्यपाल के पास बहुत सीमित अधिकार रह जाते हैं. इसलिए नगर निगम और महानगर परिषद चलाने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर कुछ तो जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए थी. पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया. इसकी वजह शुद्ध राजनैतिक थी. डर था कि इसमें इन संस्थाओं को भंग करना पड़ेगा और फिर चुनाव का रास्ता खुल जाएगा जबकि इंका दो वर्षों से इन संस्थाओं के चुनाव से मुंह छिपा रही है.

कपूर (बाएं) और बैंस: राजनैतिक कृपादृष्टि

मुख्य सचिव के पद पर विजय कपूर और डीडीए के उपाध्यक्ष पद पर के.के. बैंस की नियुक्ति से नौकरशाही हलके में खुसरफुसर शुरू हो गई

नेताओं की तरह चहेते अफसर भी बख्श दिए गए. जैसे डीडीए के आयुक्त (स्लम) मंजीत सिंह. उन्हें झुग्गी झोपड़ियों के आयुक्त के रूप में डीडीए के उपाध्यक्ष के अधिकार मिले हुए हैं. मंजीत सिंह के मातहत कर्मचारियों ने बताया कि मुख्य कार्यकारी पार्षद जगप्रवेश चंद्र अप्रैल 1987 में उनके दफ्तर आए थे. उन्होंने वादा करवा लिया कि 652 झुग्गी बस्तियों में 50 करोड़ रु. की लागत से पीने का पानी, शौचालय, नालियां और दूसरी सुविधाएं अक्तूबर तक मुहैया करा दी जाएंगी. एक इंजीनियर के मुताबिक बाद में जब महानगर परिषद के चुनाव टल गए तो उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया. उसके बाद आसानी से गाड़े जा सकने वाले हैंडपंप भर मुहैया कराए गए. नालियों के नजदीक लगाए गए इन हैंडपंपों ने हैजे और आंत्रशोथ जैसी महामारी के लिए रास्ता साफ कर दिया.

नगर निगम में अलग ही खिचड़ी पकी. 1985 से पुनर्वास बस्तियों की जिम्मेदारी लेने से बचते हुए आखिरकार निगम ने इस साल जून में उन्हें अपने हाथ में लिया. इससे पहले, मार्च में उसे इस काम के लिए ट्रक और दूसरे उपकरणों की खरीदारी के वास्ते 4.8 करोड़ रु. दिए गए थे. खरीदारी के लिए निविदाएं जारी की गईं और उपकरणों का चयन कर लिया गया. लेकिन राजनैतिक आकाओं ने इस पर आपत्ति की. उनका कहना था कि निविदाओं का भरपूर प्रचार नहीं किया गया. नतीजतन एक बार फिर आवेदन मंगाए गए. निगम के सूत्रों ने बताया कि उन्हीं कंपनियों को फिर चुना गया जिनका चयन दो माह पहले किया गया था. लेकिन इस बार कीमत 1 करोड़ रु. बढ़ गई.

शहर के किसी भी प्रशासक को ऐसे राजनैतिक हस्तक्षेपों से जूझना पड़ता है पर भंडारी को विश्वास है कि उन्हें राजनीतिकों की तरफ से किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, "मुझे उनकी कतई चिंता नहीं." नेता भी खुश हैं. इन नेताओं में सबसे ताकतवर सूचना तथा प्रसारणमंत्री हरकिशनलाल भगत ने कहा, "दिल्ली का हरेक नागरिक नए उपराज्यपाल को सहयोग देगा."

लेकिन इन तमाम वायदों के बावजूद इसकी उम्मीद कम ही है कि नए कर्ताधर्ता राजधानी की स्थिति बेहतर बना पाएंगे या ऐसी त्रासदी दुबारा होने से रोक देंगे.

इसके पहले कपूर ने भी सीधे मैदान में उतरकर मोर्चा लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. पिछले पखवाड़े वे राज निवास से गरिमापूर्ण विदाई लेकर नई दिल्ली के वसंत विहार में अपनी बेटी के घर चले गए. वे कहते हैं, "सैनिक लड़ता है और लड़ाई में हार खेत भी रहता है. मैंने वही किया जो मुझे युक्तिसंगत लगा." लेकिन उन्हें और दूसरे अफसरों को जो कीमत चुकानी पड़ी है उसके बावजूद दिल्ली को राहत मिलती नहीं दिखाई देती.

—डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिम बंगाल

मारक मिलावट

सरकारी निकम्मापन उजागर

शुरुआत पैरों के सुन्न पड़ते जाने और तेज दर्द होने से हुई. कुछ ही दिन बाद दर्जी का काम कर रहे 24 साल के सुदीप दे को पता चला कि उस पर फालिज गिर चुका है और शायद उम्र भर के लिए. यह दुख अकेले सुदीप का नहीं है. कलकत्ता के बेहला विद्यासागर अस्पताल में फालिज के मारे उनके जैसे 300 लोग और हैं, जो घिसटकर चलते समय अपने आंसुओं को बमुश्किल रोक पाते हैं. 50 साल का शिव कुमार यादव और उसके तीन बच्चे भी इनमें शुमार हैं. यादव सुबकते हुए कहते हैं, "मैं अपने बच्चों को भिखारी बनते नहीं देखना चाहता."

वे सभी कलकत्ता की झुग्गी-झोंपड़ियों में 'सामान्य' जिंदगी जी रहे थे पर अचानक जैसे कहर बरपा हो गया. कुछ व्यापारियों ने रेपसीड तेल में ट्राइक्रेसिल फॉस्फेट मिलाने की सोची. यह बेरंग और गंधहीन घातक रसायन प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होता है. फिर यह विषैला तेल बेहला की एक राशन दुकान गरीब भंडार पर बेचा गया.

शुरू में डॉक्टरों ने इसे विषाक्त भोजन की साधारण घटना ही माना. पर 17 जुलाई को रोगियों का तांता लगा रहा. विद्यासागर अस्पताल में लकवे के रोगियों की संख्या 30 तक जा पहुंची. बाद में यह संख्या बढ़कर 2,500 हो गई. इनमें 500 रोगियों का इलाज अभी भी तीन अस्पतालों में चल रहा है और 2,000 से अधिक लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविरों में उपचार करवा रहे हैं.

यह पता लगते ही कि यह विषाक्त भोजन के कारण घटी साधारण घटना नहीं है, अपराधियों की खोज शुरू हो गई. दुर्घटना के कारणों को खोज पाना कठिन नहीं था. बेइमान व्यापारियों द्वारा रेपसीड तेल (14.40 प्रति किलो) में ट्राइक्रेसिल फॉस्फेट मिलाकर उसे 26 रु. प्रति किलो के भाव से सरसों का तेल कहकर बेचने की बात नई नहीं है.

लेकिन किसी एक को इस त्रासदी का जिम्मेदार ठहराना इतना आसान नहीं था. एक-दूसरे पर दोषारोपण के चलते ऐसा लगने लगा कि जैसे सरकार खुद पंगु हो गई हो. खाद्य और नागरिक आपूर्तिमंत्री निर्मल बोस ने कहा, "हमारी जिम्मेदारी दुकानों पर सामान पहुंचाने भर की है, उसके बाद का जिम्मा तो नगर निगम का है." इस पर महापौर कमल बसु का जवाब था कि उनके खाद्य निरीक्षकों को राशन दुकानों की जांच करने का अधिकार ही नहीं है. यह दलील गलत साबित होने पर महापौर ने दूसरा बहाना बनाया कि राशन वितरण व्यवस्था ठप हो जाने के अंदेशे से छापे नहीं डाले गए.

मंत्री और महापौर के बीच आरोपों-प्रत्यारोपों से सत्ताधारी वाममोर्चे में सत्ता के लिए चल रही रस्साकशी ही जाहिर होती है. बसु माकपा के नेता हैं जबकि बोस फारवर्ड ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं. ऐसी लापरवाही से आगबबूला होकर मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने महापौर को राशन दुकानों के मालिकों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया और 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया. लेकिन खुद ज्योति बसु भी पीड़ित लोगों को देखने नहीं गए. उन्होंने बस इतना किया कि अपने निवास पर एक बैठक बुलाकर मिलावट विरोधी अभियान छेड़ने का आदेश दिया और लकवापीड़ितों के मुफ्त इलाज के अलावा उनमें हरेक को 500 रु. आर्थिक मदद देने की घोषणा की.

उधर इंका को लगा कि इस मुद्दे का राजनैतिक फायदा मिल सकता है. इंका सांसद ममता बनर्जी ने, जिनके चुनावक्षेत्र में बेहला भी आता है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार, केंद्रीय राजस्व राज्य-मंत्री अजीत पांजा और केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री मोतीलाल वोरा के दौरे की व्यवस्था भी कर डाली. पांजा ने तो लकवापीड़ितों को 500-500 रु. भी बांटे. कूच बिहार में विरोध-सभाएं आयोजित की गई, जिसमें पुलिस की गोली से दो इंका कार्यकर्ता मारे गए.

दूसरी ओर हादसे के काफी देर बाद तैनात डॉक्टरों के दल ने इन लक्षणों को 'असेंडिंग टॉक्सिक न्यूरोपैथी' बताया. बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के एक डॉक्टर के मुताबिक इस रोग से पीड़ित व्यक्ति "जीवन भर पैर घसीटकर चलने को मजबूर होंगे." जिन लोगों पर फालिज का हल्का प्रकोप है वे तो धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगे. लेकिन जिन पर इसकी भारी मार पड़ी है उनके ठीक होने की ज्यादा उम्मीद नहीं. पर सरकार का पंगुपन भी उतना ही चिंताजनक है.

—कमलजीत रतन

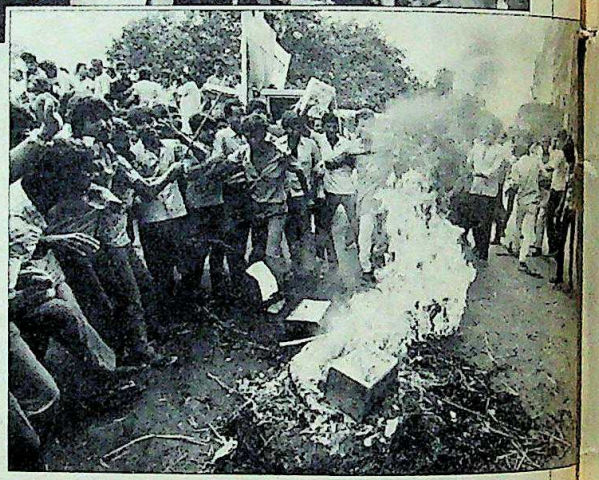

अस्पताल में रोगियों से मिलते वोरा; और (दाएं) हादसे के विरोध में प्रदर्शन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

बदनामी के छींटे

विवाद से सरकार परेशान

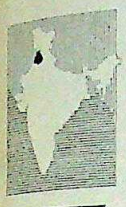

चंडीगढ़ में बड़े लोगों की जिंदादिल पार्टियों में पंजाब सरकार के जन-संपर्क विभाग के सचिव एल. एल. खुराना का नाम जाना-पहचाना है. मेजबानी के लिए विख्यात खुराना के मेहमानों की सूची शहर के उन संभ्रांत लोगों की नाम निर्देशिका-सी लगती है जो सचिव महोदय के बंगले के जगमगाते लॉन में देर रात तक पीते और बतियाते हैं.

पिछले महीने भी उनके घर ऐसी ही एक पार्टी हुई. मेहमानों में आईएएस और आईपीएस अफसर थे, तो कुछ पत्रकार भी. लेकिन आकर्षण का केंद्र पंजाब पुलिस के महानिदेशक 54 वर्षीय कंवरपाल सिंह गिल थे. पिछले जून में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान हर शाम टीवी पर नई खबर देने वाले गिल का चेहरा सारे देश के लिए वैसे भी जाना-पहचाना है.

पर पार्टी वाले दिन उनकी अंतर्मुखी छवि गायब थी. नशे में बहके हुए वे 60 साल से ऊपर के और अभी कुंवारे, जाने-माने डॉ. पी.एन. चुट्टानी के संग लॉन के उस कोने की ओर बढ़ते जा रहे थे जहां महिलाएं अपनी ही महफिल जमाए बैठी थीं. उनमें वित्त विभाग की विशेष सचिव, गोरी-चिट्टी, 43 वर्षीया रूपन देओल बजाज भी थीं.

बजाज के मुताबिक झमेला उस वक्त शुरू हुआ जब गिल ने उन्हें अपने पास बैठने का न्यौता दिया. वे कहती हैं, "शुरू में जब उन्होंने मेरी कुर्सी अपनी ओर घसीटी तो मैंने अनदेखी कर दी. मैंने हौले से अपनी कुर्सी पीछे सरका ली. पर उनके दुबारा ऐसा करने पर मैं रूखाई से उठकर चली आई."

करीब 10 मिनट बाद पुलिस प्रमुख भी उनके पीछे-पीछे चले आए और उनसे सटकर खड़े हो गए. बजाज के मुताबिक गिल ने उंगली उठाकर धमकी की मुद्रा में उन्हें अपने साथ चलने को कहा. गिल ने अपना यह आदेश—तुरंत उठकर मेरे साथ चलो—कम-से-कम तीन बार दिया.

स्थिति ज्यादा बिगड़ती, इससे पहले ही बजाज अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुईं और गिल ने झुककर उनके नितंबों पर हाथ दे मारा. हर कोई आश्चर्यचकित रह गया. कई मेहमानों ने बजाज को गिल से यह कहते सुना कि "तुम बहुत बेहूदे हो और अच्छी संगति के लायक नहीं." इस पर मेजबान बीच-बचाव करके गिल को बाहर ले गए.

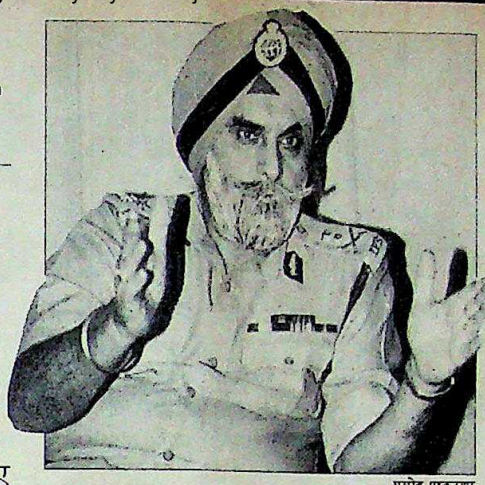

प्रमोद पुष्करणा

द इंडियन पोस्ट

शुरू में तो गिल खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन बाद में रिबेरो और मुख्य सचिव आर.पी. ओझा की मौजूदगी में बजाज से माफी मांगने को राजी हो गए

कहानी यहीं से शुरू हुई. 'सिद्धांतों की लड़ाई' लड़ते हुए गुस्से में भरी बजाज ने राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय सहित दूसरे उच्चाधिकारियों से शिकायत की. राज्यपाल के सलाहकार जूलियो रिबेरो जब बजाज से 'भूलो और माफ करो' की सलाह मनवाने में नाकाम रहे तो दो दिन बाद उन्होंने राय को चिट्ठी भेजी. उन्होंने लिखा कि बजाज का अपमान हुआ है और वे इस पर कार्रवाई करने की अपनी मांग छोड़ने को तैयार नहीं. इधर बजाज ने गिल पर अशोभनीय व्यवहार और हमले का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी.

अफसरशाही के भीतर प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं. एक वरिष्ठ आईएएस अफसर कहते हैं, "शिकायत 10 दिन बाद दर्ज कराई गई, यह गिल के खिलाफ षड्यंत्र लगता है." कई दूसरों का मानना था कि यह आईएएस और आईपीएस अफसरों के बीच चल रहे विवाद का एक और लक्षण है. राज्य के आईएएस अफसर प्रशासन पर पुलिसवालों, खासकर गिल और रिबेरो के दबदबे के कारण अरसे से खार खाए हैं.

इस घटना से पहले बजाज और गिल अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं थे. बजाज कहती हैं कि उनकी पहले एक ही बार गिल से भेंट हुई थी जब वे अपने आईएएस पति भारत बजाज के खिलाफ सीबीआई द्वारा बनाए गए एक मामले में अपने वकील के कहने पर गिल से सलाह लेने गई थीं.

अमूमन अंतर्मुखी रहने वाले गिल कुछ ही पेग चढ़ाने के बाद अक्सर प्रचंड हो उठते हैं. असम (जहां गिल डीआईजी रह चुके हैं) और पंजाब दोनों जगह पार्टियों में महिलाओं के साथ शर्मिंदगी वाला व्यवहार करने में उनका नाम रहा है.

खुद गिल बेहद पराजित-से लगे. उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया. वे तुरंत अमृतसर रवाना हो गए और करीब एक हफ्ता बाहर रहे. शुरू में हालांकि उन्होंने खुद को बेकसूर बताया पर बाद में वे रिबेरो और मुख्य सचिव आर.पी. ओझा की मौजूदगी में बजाज से माफी मांगने को राजी हो गए. लेकिन बजाज ने यह पेशकश ठुकरा दी और गिल को दंड देने की मांग की, हालांकि उन्हें अंदेशा है कि गिल को छोड़ दिया जाएगा. वे राय की इस टिप्पणी को इसका निश्चित संकेत मानती हैं—"गिल आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं अतः राष्ट्रहित में हम उन्हें न हटाएं."

फिर भी बजाज ने लड़ाई जारी रखने की ठान रखी है. इससे सरकार दुविधा में फंस गई है. गिल को हटाने से आतंकवादियों के खिलाफ जेहाद में उसके सेनापति की बलि चढ़ जाती है. पर अगर वह ऐसा नहीं करती तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कमान ऐसे पुलिस प्रमुख के हाथ में रहेगी जिसकी प्रतिष्ठा संदेहास्पद है. आतंकवादी इस घटना को निश्चय ही पुलिस के खिलाफ प्रचार में इस्तेमाल करेंगे जो सरकार के लिए शायद ठीक नहीं होगी.—**विपुल मुद्गल**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

बेतुकी कार्रवाई

'अजीत' पर देशद्रोह का मुकदमा

कई वर्षों से पंजाब में हालत यह है कि प्रशासन के दाएं हाथ को खबर नहीं है कि बायां हाथ क्या करता रहा है. इसकी जीती-जागती मिसाल है राज्य में सर्वाधिक बिकने वाले पंजाबी दैनिक (प्रसार संख्या 1.5 लाख) 'अजीत' के खिलाफ सरकार की कार्रवाई.

इस अखबार में 18 से 22 जुलाई तक एक विज्ञापन छापने पर सरकार ने इसके संपादक और प्रकाशक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया. इस विज्ञापन में दुर्दांत आतंकवादी लाभ सिंह उर्फ सुक्खा सिपाही की भोग रस्म की सूचना दी गई थी. सरकार का आरोप है कि यह विज्ञापन छापने से आतंकवादियों का महिमामंडन हुआ. सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यह कार्रवाई तकरीबन उसी वक्त की गई जब 'अजीत' के युवा संपादक बरजिंदर सिंह को प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते में शरीक होने का न्यौता दिया गया.

मामले की गुत्थियां तो अलग, अखबार के खिलाफ कार्रवाई के पीछे सरकारी दलील यह है कि यह विज्ञापन आतंकवादी लाभ सिंह के बारे में था, और इसमें उसे 'शहीद' बताया गया था. लेकिन सचाई यह है कि ऐसे विज्ञापन पंजाब के क्षेत्रीय अखबारों में अक्सर छपते रहे हैं. जालंधर से छपने वाले ज्यादातर अखबार इस तरह के विज्ञापन छाप चुके हैं. यहां तक कि चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित ट्रिब्यून समूह के पंजाबी ट्रिब्यून ने 28 नवंबर, 1987 को एक 'शहीदी समागम' का विज्ञापन छापा था.

यह बात तो अब जगजाहिर है कि पंजाबी के अखबारों के लिए इन विज्ञापनों को छापने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि इन्हें छपवाने के लिए ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन का कोई पदाधिकारी अखबारों के दफ्तर में अक्सर आ धमकता है. जालंधर के एक अखबार के संपादक ने स्वीकार किया, "आप इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते. इनकार का मतलब है अपना नाम हिट लिस्ट में दर्ज करवाना." चंडीगढ़ में 'अजीत' के विशेष संवाददाता हरकंवलजीत सिंह कहते हैं, "जब विज्ञापन और प्रेस विज्ञप्तियां धमकियों के साथ आएं तो आप कर भी क्या सकते हैं? लेकिन सरकार है कि हमें राष्ट्र विरोधी करार देती है." उनकी आशंकाएं बेबुनियाद भी नहीं हैं. तकरीबन दर्जन भर पत्रकारों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, जबकि कई पत्रकारों, संपादकों पर सरकार ने आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में मुकदमे चला रखे हैं.

विडंबना तो यह है कि 'अजीत' को एक नरमपंथी अखबार माना जाता है. इसके प्रतिद्वंद्वी अखबार 'अकाली पत्रिका' की बिक्री इसके तीखे तेवर के कारण कुछ वर्षों में बढ़ी है. 'अजीत' के पुराने मालिक थे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता सरदार बलदेव सिंह. बाद में उन्होंने इसे बरजिंदर सिंह के पिता साधू सिंह हमदर्द को बेच दिया. साधू सिंह ने अखबार की साख बढ़ाई. मरने से पहले उन्होंने अखबार चलाने के लिए एक ट्रस्ट बना दिया. आजकल इस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदेश इंका उपाध्यक्ष दिलबाग सिंह हैं. ट्रस्टियों में नरमपंथियों का बोलबाला है. इनमें ज्ञानी जैल सिंह के दामाद एस.एस. विरदी, पूर्व मंत्री रवेल सिंह और पंजाब के पूर्व महाधिवक्ता अजीत सिंह सरहदी शामिल हैं. संत हरचंद सिंह लोंगोवाल और जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर सरीखे लोग भी इसके ट्रस्टी रह चुके हैं.

पंजाब सरकार बरजिंदर सिंह को पत्रकारिता के अपने सबसे बड़े पुरस्कार 'पत्रकार शिरोमणि' से सम्मानित कर चुकी है. बरजिंदर सिंह ने राजीव-लोंगोवाल समझौता वार्ता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कुलदीप नैयर कहते हैं, "सांप्रदायिक तत्वों, आतंकवादियों और सरकार के दबावों के आगे कभी न झुकने वाले एक संपादक के खिलाफ की गई कार्रवाई बेहद बेतुकी है." इस बीच बरजिंदर सिंह ने अपना पक्ष अखबार के पहले पन्ने पर संपादकीय लिखकर रखा है, "प्रधानमंत्री की ऊंची कुरसी पर बैठे शख्स ने 'अजीत' पर ऐसे आरोप लगाकर हरेक पंजाबी को ठेस पहुंचाई है और नाराज किया है." संसद में

प्रमोद पुष्करणा

संपादक बरजिंदर सिंह; और (बाएं) 'अजीत': दमन का विरोध

'अजीत' का मामला जनता पार्टी नेता मधु दंडवते ने उठाया. बहस के दौरान गृहमंत्री बूटा सिंह तक ने स्वीकार किया कि 'अजीत' के संपादक की देशभक्ति पर शक करने की कोई वजह नहीं है. लेकिन उन्होंने कहा कि अखबार को स्पष्टीकरण देना ही होगा. चंडीगढ़ में पंजाब के जनसंपर्क विभाग के प्रधान एस.एल. कपूर का कहना था कि विज्ञापनों की वजह से सरकार नाराज तो है लेकिन 'अजीत' के संपादक यह गलती बिना शर्त कबूल कर लें तो मामला रफादफा हो सकता है.

फिलहाल स्थिति यह है कि पत्र-पत्रिकाओं और विपक्ष द्वारा मचाए जा रहे तमाम शोर से 'अजीत' बेखबर नजर आ रहा है. और इतना तो उसे लाभ हुआ ही है कि मुकदमा दायर होने के एक हफ्ते के भीतर ही इसकी बिक्री 10,000 बढ़ गई है.

—विपुल मुद्गल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नगालैंड

लोकतांत्रिक प्रक्रिया ताक पर

इंका की सरकार न रही तो विपक्ष की भी न बनने दी

आठ महीने पहले इसे इंका की चुनावी किस्मत फिर से जाग उठने की शुरुआत बताया जा रहा था. विद्रोहग्रस्त नगालैंड के इतिहास में पहली बार पार्टी ने विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था. नतीजे के तौर पर प्रतिष्ठित नगा नेता होकिशे सेमा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे. लेकिन पिछले पखवाड़े सेमा सरकार के औंधे मुंह गिरने और राज्यपाल जनरल के.वी. कृष्णराव द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश से पार्टी को जबरदस्त झटका लगा. विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया.

दरअसल सेमा की मुश्किलें कुछ समय पहले ही शुरू हुई थीं. भ्रष्टाचार से ग्रस्त इस राज्य में सेमा ने अपने कड़े रवैये से बड़े-बड़ों की नींद हराम कर दी थी. पर उन्होंने ऐसे समय भारत महोत्सव में शामिल होने के लिए तोक्यो जाने की भूल कर दी जब राज्य में स्थिति गरमा रही थी दरअसल, सेमा और उनकी पत्नी उस समय छुट्टी पर थे कि 60 सदस्यों वाले सदन में इंका के 34 में से 13 विधायकों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व से असंतोष जाहिर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सी. चोंगसेन को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

चार प्रमुख मंत्रियों और विधानसभा उपाध्यक्ष सहित 13 विधायकों ने घोषणा की कि उन्होंने 17 विधायकों वाली नगा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (एनएनडीपी) से गठजोड़ कर लिया है. विद्रोहियों ने दावा किया कि वे एनएनडीपी और अब तक इंका को समर्थन दे रहे चार निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं. लेकिन इंका को सबसे बड़ा झटका तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्षी गठजोड़—संयुक्त क्षेत्रीय विधायक दल को एक नए राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करने से लगा. इससे असंतुष्ट दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आने से भी बच गए और उनके लिए सरकार पलटने का रास्ता साफ हो गया.

तख्तापलट की यह कोशिश इस कदर जोर पकड़ चुकी थी कि इंका आलाकमान के संकटमोचक सड़क परिवहनमंत्री राजेश पायलट का कोहिमा दौरा भी मामले को सुलझा नहीं पाया. इसके बाद घटनाचक्र बहुत तेजी से घूमा. पूर्व वित्तमंत्री और एक समय नगा बागियों के ब्रिगेडियर रह चुके, विपक्षी नेता वामुजो को नए गठबंधन का नेता चुन लिया गया. 34 विधायकों के नामों की फेहरिस्त लेकर वे मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे जहां राज्यपाल राव पड़ाव डाले हुए थे. उन्होंने मांग की कि राव को सेमा मंत्रिमंडल बरखास्त करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए. लेकिन राव ने इस मांग पर टालमटोल की.

इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह भी कोहिमा पहुंच गए. बागी गुट का आरोप है कि बूटा सिंह ने धमकी दी कि अगर उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा. उधर, नगा स्टुडेंट्स फेडरेशन ने चेतावनी दी कि केंद्र नगालैंड के भविष्य का फैसला स्थानीय लोगों पर ही छोड़ दे तो बेहतर होगा.

हड़बड़ाहट में केंद्र ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने को कहा. फैसले को सही ठहराते हुए पायलट कहते हैं, "सिद्धांतहीन गठबंधन को सत्तासीन होने देने से खतरा यह था कि इस संवेदनशील राज्य में अस्थिरता पैदा हो जाती."

पर असंतुष्टों ने पायलट के बयान को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने बागियों को इंका में वापस लाने के लिए धमकाने और मान-मनौवल की जी-तोड़ कोशिशें कीं. विद्रोही गुट के नेता के.एल. चिशी का कहना है कि पायलट ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच दिया.

इन आरोपों के जवाब में पायलट और इंका के दूसरे नेता कहते हैं कि बागियों ने सेमा का साथ महज इसलिए छोड़ा क्योंकि

होकिशे सेमा

नए गठबंधन के निर्वाचित नेता वामुजो ने राज्यपाल से मांग की कि सेमा सरकार को बरखास्त कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए

वामुजो

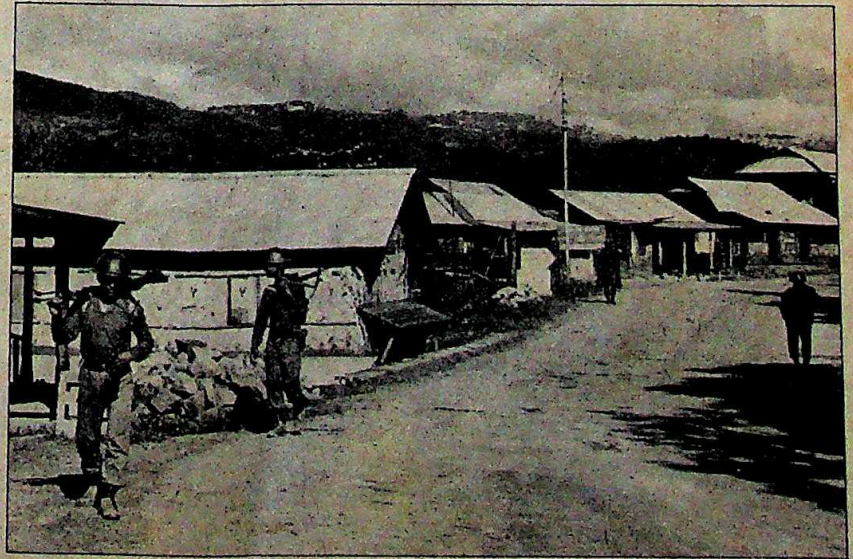

कोहिमा राजमार्ग पर गश्त लगाते असम राइफल्स के जवान: फिर अशांति

प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुख्यमंत्री ने उन लोगों को पैसा बटोरने की छूट नहीं दी. सेमा भी कहते हैं, "अगर मैंने समझौता कर लिया होता तो यह नौबत नहीं आती. बहरहाल मैं सभी 34 विधायकों को मंत्री नहीं बना सकता था."

भले ही ये आरोप सही हों लेकिन गठबंधन को विधानसभा अध्यक्ष की मान्यता मिल जाने के बाद भी वामुजो को सरकार बनाने का मौका न देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता. दरअसल विधानसभा भंग करने की सिफारिश का राज्यपाल का फैसला सरासर पक्षपातपूर्ण है. राज्यपाल की यह दलील कि, "ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य सरकार को संविधान की शर्तों के अनुसार चलाना मुमकिन नहीं रहा," मुलम्मेबाजी ही लगती है. क्रुद्ध वामुजो ने जहां राव को 'केंद्र की कठपुतली' करार दिया, वहीं दिल्ली में समूचे विपक्ष ने केंद्र को राज्यपाल की 'सुनियोजित रिपोर्ट' मान लेने पर 'लोकतंत्र को तहस-नहस करने' का दोषी ठहराया.

जाहिर है कि इंका नगालैंड को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती, भले ही इसके लिए उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार क्यों न करना पड़े. लेकिन पार्टी के लिए ऐसा करना टेढ़ी खीर साबित होगा. वामुजो कहते हैं, "इस कार्रवाई से भारत-विरोधी भावनाएं ही भड़केंगी." वे सही भी हो सकते हैं. लेकिन सबसे दुखदायी बात यह है कि राज्य सरकार ऐसे समय में धराशायी हुई है जब प्रमुख बागी गुट नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड अंदरूनी रस्साकशी के चलते बहुत कमजोर पड़ गया था.

बहरहाल, इस उत्तर-पूर्वी राज्य में डांवाडोल राजनैतिक स्थिति के चलते बागियों के लिए दम मारने का इससे बेहतर मौका और कौन-सा हो सकता है. —रमेश मेनन

एन.टी. रामराव

राजनीति सिखाएंगे

छह साल पहले फिल्मों से राजनीति के क्षेत्र में उतरे मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव विनम्रता से खुद को 'राजनीति में अभी बच्चा' कहते हैं. लेकिन यह 'बच्चा' अब औरों को राजनीति की फिसलन भरी राह पर चलने के गुर सिखाने के लिए तैयार हो गया है. इस राह पर चलने की आकांक्षा लिए 22 प्रत्याशियों ने पिछले पखवाड़े उनके 'राष्ट्रीय राजनैतिक जागरण संस्थान' (एनआईपीसी) के नौ महीने के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है.

रामराव कहते हैं, "अब लोगों का यह भ्रम दूर करने का समय आ गया है कि राजनीति ऐसा पेशा है जिसमें किसी खास काबिलियत की जरूरत नहीं होती." राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बताते हैं, "अब देश की राजनीति को नौसिखुओं, अवसरवादियों, सत्ता के दलालों के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता."

इसी मकसद से हैदराबाद के नजदीक गांधीपेट में तेलुगु देशम पार्टी के मुख्यालय में नौसिखुओं को काफी सख्त कसौटी पर कसा जाएगा. उन्हें हर रोज तड़के 4.45 बजे उठना पड़ेगा और 90 मिनट तक शारीरिक व्यायाम, योगासन और ध्यान करना होगा. उसके बाद भाषणों का दौर चलेगा. आखिरकार रात 10 बजे उन्हें इस मशक्कत से छुट्टी मिलेगी.

पहले सात महीने मौजूदा आर्थिक मुद्दों, राजनैतिक स्थिति, प्रशासन, सामान्य कानून आदि की शिक्षा दी जाएगी. भाषण सुनने के अलावा प्रशिक्षणार्थियों को तब तक सीखे गए पाठों के बारे में खुद भी लिखना-पढ़ना होगा. इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे. दो महीने तक उन्हें इलाकों में अध्ययन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के काम में लगाया जाएगा.

यह प्रशिक्षण वाकई काफी कठिन दिखता है. एनआईपीसी के निदेशक प्रोफेसर बी. प्रसाद राव कहते हैं, "इसी वजह से हम इसमें सिर्फ जनसेवा की भावना वाले स्नातकों को ही शामिल कर रहे हैं. हमने बहुतों को यह कहकर लौटा दिया कि उन्हें यहां से जो डिप्लोमा मिलेगा उसकी किसी विश्वविद्यालय से मान्यता नहीं होगी और इससे उन्हें नौकरी पाने में भी मदद नहीं मिलेगी." इस चेतावनी से उत्साही लोगों की संख्या घटी. 310 आवेदकों में 70 को चुना गया पर आखिरकार 1 अगस्त को सिर्फ 22 प्रत्याशियों ने ही दाखिला लिया. यहां के छात्रों में जबरदस्त उत्साह है. राज्य विद्युत बोर्ड में इंजीनियर रह चुके पूर्वी गोदावरी जिले के एक सरपंच नंदमूरि बलैया कहते हैं, "इस पाठ्यक्रम से हमारी सोच-समझ व्यापक होने में सहायता मिलेगी." नरसिंहा नायडू का भी कहना है कि उनके दाखिला लेने का मुख्य कारण यह है कि "अन्नागारू (बड़े भाई) गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं और इस पाठ्यक्रम से हमें तेलुगु देशम के बारे में गांववालों को बताने में सहायता मिलेगी."

हालांकि निजी तौर पर कई मानते हैं कि वे अगले चुनाव में तेलुगु देशम की टिकट की उम्मीद लगाए हैं. प्रसाद राव को भी लगता है कि जो अव्वल आएंगे उन्हें तेलुगु देशम की 'जिम्मेदारियां' दी जाएंगी. लेकिन तेलुगु देशम की राजनैतिक शैली को ध्यान में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि इन नौसिखुओं को मनचाही मुराद पाने के लिए रामराव की खिदमत करने जैसे गुर भी सीखने होंगे. —अमरनाथ के. मेनन.

बाबजी/जनता स्टूडियो

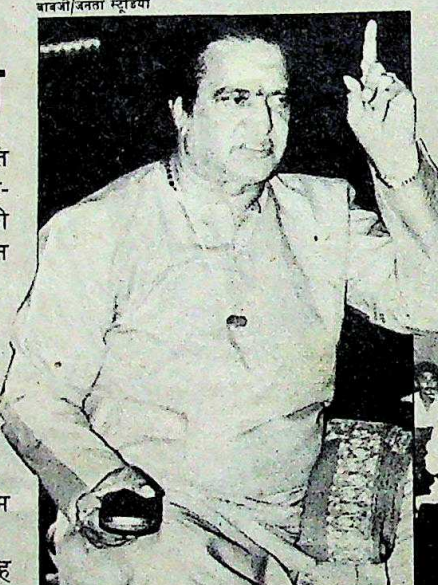

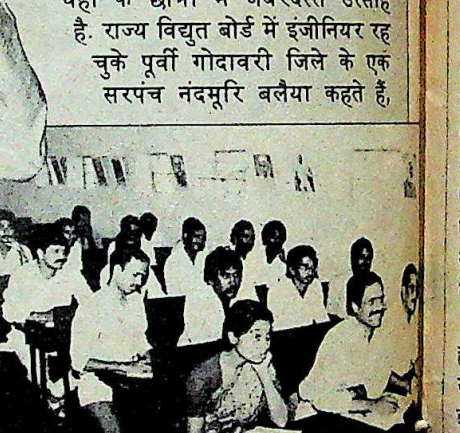

रामराव (ऊपर); एक भाषण में भाग ले रहे प्रशिक्षणार्थी: दांवपेच की शिक्षा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सैयद मोदी

रहस्यमय हत्या

अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा

पिछले आठ साल से बैडमिंटन के राष्ट्रीय चैंपियन, 28 वर्षीय सैयद मोदी के लिए 28 जुलाई का दिन भी सामान्य दिनों की ही तरह था. हमेशा की तरह उस दिन शाम 7.30 बजे लखनऊ के के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में अपना अभ्यास खत्म कर वे स्टेडियम के दरवाजे पर बने रेस्तरां तक आए, ठंडा पेय पिया और घर जाने के लिए अपने स्कूटर से मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए. लेकिन वे घर कभी नहीं पहुंच पाए.

जैसे ही उनका स्कूटर स्टेडियम के दरवाजे से बाहर निकला, दो युवकों ने 0.38 बोर के रिवाल्वर से उन पर दनादन पांच गोलियां दाग दीं. जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक दोनों हत्यारे एक सफेद मारुति कार पर सवार हो कर उलटी दिशा में फरार हो गए.

इस अप्रत्याशित नृशंस हत्या से पूरा लखनऊ सन्न रह गया. लखनऊ रेंज के डीआईजी सुरेशपाल सिंह कहते हैं, "लाख कोशिशों के बावजूद हम यह पता लगाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि मोदी से किसी की दुश्मनी भी थी. इसीलिए इस हत्या का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा."

यहां तक कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को भी कुछ हाथ नहीं लगा है. 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है पर उससे भी कुछ नहीं निकला. मोदी के मित्र और कई साल से उनके साथ खेल रहे 25 वर्षीय परवेज अहमद से भी पूछताछ की गई. परवेज कहते हैं, "मोदी और हत्या—इन दो शब्दों का कहीं दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं बैठता. उसके जैसा मासूम आदमी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं."

सभी फोटो: आर.के. गुप्त

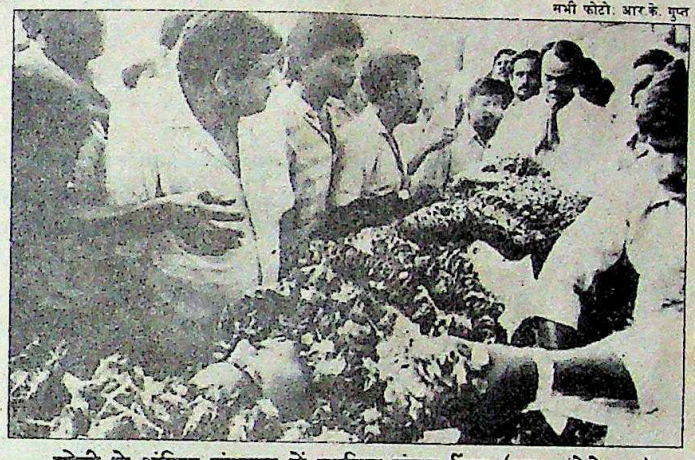

मोदी के अंतिम संस्कार में शामिल संजय सिंह (हाथ जोड़े हुए)

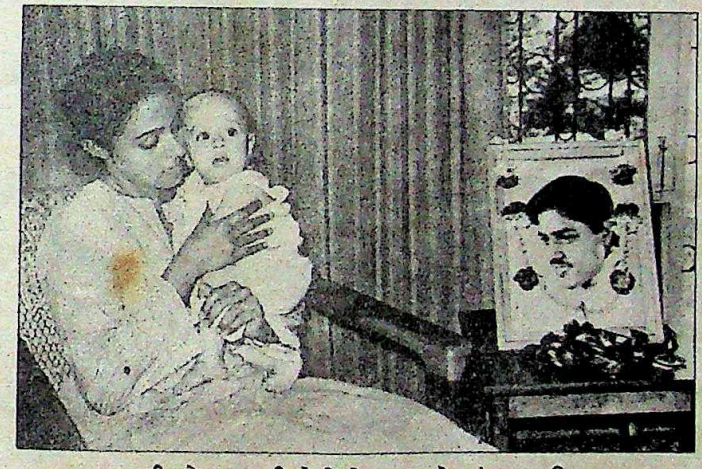

अपनी दो माह की बेटी के साथ शोकसंतप्त अमिता

वह जगह जहां मोदी को गोली मारी गई

मोदी की शोकसंतप्त पत्नी, 24 वर्षीया अमिता कहती हैं, "मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति जैसे सीधे-सादे इंसान की आखिर कोई क्यों हत्या करेगा." बैडमिंटन की राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी अमिता कुलकर्णी का सैयद मोदी से विवाह दो साल तक प्यार चलने के बाद 1984 की मई में हुआ था और अभी दो महीने पहले उन्हें पहली संतान हुई थी.

पिछले सप्ताह तक खुफिया एजेंसियों को सिर्फ इतना समझ में आया है कि मोदी की हत्या बड़े योजनाबद्ध ढंग से की गई और हत्यारे शायद भाड़े पर बुलाए गए पेशेवर लोग थे. साथ ही यह भी कि हत्या के जिम्मेदार व्यक्ति मोदी से व्यक्तिगत रूप से या उनके पेशे से जुड़े हैं. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से मोदी उत्तर-पूर्व रेलवे में, जहां वे नौकरी करते थे, उनके खिलाफ की गई एक शिकायत के कारण काफी परेशान रहा करते थे. शिकायत की गई थी कि वे राजीव विरोधी हो गए हैं और जनमोर्चा के कार्यकलापों से जुड़ रहे हैं. यह आरोप जनमोर्चा नेता संजय सिंह से उनके संबंधों के कारण लगाया गया. शिकायत उत्तर प्रदेश के इंका सांसद काजी जलील अब्बासी के नाम से 26 अगस्त 1987 को दर्ज कराई गई थी.

उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ दफ्तर ने 28 जनवरी 1988 को मोदी का लखनऊ से गोरखपुर तबादला कर दिया. लेकिन इस शिकायत की खुफिया जांच कराने पर पाया गया कि यह निराधार थी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसके बाद मोदी रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया से मिले और अंततः उनका तबादला रद्द हो गया. लेकिन इस उलटफेर में लखनऊ दफ्तर ने उनका वेतन जनवरी से जून '88 तक रोके रखा. अब्बासी के नाम से शिकायत दरअसल उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के सचिव डॉ. विजय सिन्हा ने की थी. सिन्हा मोदी से संघ के खिलाफ कई बातें अखबारवालों को बताने के कारण नाराज थे. सिन्हा ने कबूल भी कर लिया है कि उन्होंने फर्जी शिकायत की थी.

इस बीच स्थानीय अखबारों और चर्चाओं में एक और अटकलबाजी जोर पकड़ रही है. अमिता के साथ संजय सिंह और मोदी परिवार के घनिष्ठ मित्र, सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सुब्रत राय का नाम एक 'प्रेम त्रिकोण' में जोड़ा जा रहा है. संजय सिंह और सुब्रत राय दोनों ने ही ऐसे किसी संबंध का खंडन किया है. अमिता भी इसका खंडन करती हैं. वे कहती हैं, "एक तो मुझसे मेरा पति छिन गया और अब मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है."

यह त्रासदी ऐसे समय पर हुई जब सैयद और अमिता छह महीने के लिए लखनऊ से बंबई जाने की तैयारी कर रहे थे.

लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था. मोदी की हत्या जांच एजेंसियों के लिए गुत्थी तो बनी ही हुई है, भारतीय बैडमिंटन को इससे अपूरणीय क्षति पहुंची है. प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस हत्या पर शोक संदेश जारी किए. इस कारण भी मामला जांच एजेंसियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है. लेकिन जिस हत्या के कारणों का पता ही न चल पा रहा हो, उसकी गुत्थी सुलझाना टेढ़ी खीर ही साबित होगी.

—दिलीप अवस्थी

प्रतिभा पलायन

करनी कुछ और

भारत सरकार देश से प्रतिभा पलायन का रुख पलटना चाहती है. उसने बाधाएं हटा दी है; प्रक्रिया सरल बना दी है; कई प्रोत्साहन दिए हैं; परस्पर सहयोग की संधियों पर दस्तखत किए हैं. और सबसे बड़ी बात कि वह विदेशों में बस गए पेशेवर और अपने क्षेत्र में महारत रखने वाले व्यक्तियों से मुल्क लौटने का आह्वान कर रही है. क्या ये सारी बातें सही हैं? कम-से-कम छह नाइजीरियाई विश्वविद्यालयों से डिग्री लेने वाले 60 डॉक्टरों के अनुभव से तो ऐसा नहीं लगता. पिछले चार बरस से वे अपने मुल्क—भारत—लौटकर काम शुरू करना चाहते हैं पर लालफीताशाही उन्हें आसपास भी फटकने नहीं दे रही.

सरकारी नियमों के हिसाब से देसी और विदेशी मेडिकल संस्थानों की डिग्रियों को मान्यता देने का अधिकार भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को है. मान्यता देने से पहले यह संबद्ध संस्थान का निरीक्षण करती है, भले ही वह देश में हो या विदेश में. पर रुकावट यह है अपने निरीक्षकों को विदेश भेजने के लिए रकम की मंजूरी का अधिकार स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है और मंत्रालय 60 डॉक्टरों के इस मामले में नाइजीरिया जाकर संस्थाओं का निरीक्षण करने की परिषद की मांग पर आराम से पालथी लगाए बैठा हुआ है.

सबसे पहले नाइजीरिया से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली कलकत्ता की संगीता सेनगुप्त ने 1984 में सरकार को अर्जी दी थी. तबसे डॉक्टरों की अर्जियों की परिषद से स्वास्थ्य मंत्रालय तक आमदोरफ्त लगातार चल रही है. परिषद के महासचिव पी.एस. जैन कहते हैं, "अगर हम भारतीय संस्थानों का इतनी सावधानी से निरीक्षण करते हैं तो विदेशी संस्थानों और विश्वविद्यालयों से भेदभाव क्यों किया जाए."

कार्टून अजीत नैनन

एमसीआई का पैमाना काफी सख्त है. मेडिकल संस्थान में 11 विभिन्न विभाग होने चाहिए जहां 38 विषयों की पढ़ाई होती हो. मान्यता देने से पहले परिषद इनके ब्यौरे की तस्दीक करती है.

नाइजीरिया के डॉक्टरों का दावा है कि उनकी डिग्री को अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा कई राष्ट्रमंडल देशों में मान्यता मिली हुई है और यह बात भारत सरकार को बता दी गई है. फिलहाल भारत ने 36 देशों के 150 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों और संस्थानों की डिग्रियों को मान्यता दे रखी है.

यात्रा भत्ते के अनुरोध को दबा लेने के पीछे स्वास्थ्य मंत्रालय का तर्क है कि अगर वह परिषद के दल को नाइजीरिया जाने की इजाजत दे देती है तो ऐसी और भी गुजारिशें आने लगेंगी क्योंकि तकरीबन बारह देशों में पढ़े डॉक्टर भी भारत लौटना चाहते हैं. एमसीआई के अध्यक्ष ए.के.एन. सिन्हा बताते हैं, "हमने सरकार को सुझाव दिया है कि वह विदेशों से पढ़कर आए भारतीय डॉक्टरों की जानकारी का स्तर जांचने के लिए उनकी परीक्षा ले."

पर बाधा यह है कि परिषद को इस परीक्षा का अधिकार देने के लिए कानूनी संशोधन की जरूरत पड़ेगी. इसमें कई बरस लग जाएंगे. यानी प्रतिभा पलायन का रुख तब तक पलटा नहीं जा सकेगा.

—पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार

असंतोष की अनबुझी आग

आजाद की सुरक्षात्मक कार्रवाइयां लंबे समय तक कारगर न होंगी

छह महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद का कार्यकाल धूम-धड़ाके से शुरू हुआ था लेकिन पिछले महीने हुई घटनाओं से संकेत मिलता है कि इसका नामालूम अंत हो सकता है. आजाद का सुख-चैन विपक्ष ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने छीना है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों ने उनकी धुंआधार आलोचना तो की ही, इस महीने के शुरू में 60 असंतुष्ट विधायक उनके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वार पर दस्तक देने दिल्ली भी जा पहुंचे.

इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने तो खुलेआम कह ही दिया था कि आजाद सरकार पूर्ववर्ती विंदेश्वरी दुबे सरकार से किसी मायने में बेहतर नहीं है. हालांकि बाद में मिश्र ने आजाद को 'पूरा समर्थन' देने का बयान भी जारी किया, लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका. आजाद की मुश्किलों का सिलसिला यहीं नहीं थमा. प्रदेश इंका के अध्यक्ष और सांसद तारिक अनवर ने राज्य की 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. उनका आरोप था कि आजाद पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं और उन्होंने जिला इंका अध्यक्षों को जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाने का वायदा भी पूरा नहीं किया.

मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा के एक फैसले की वजह से तो मुसीबत में ही फंस गए. झा ने फैसला दिया कि विधान-सभा में आजाद सदन के नेता नहीं हो सकते क्योंकि वे विधान परिषद के सदस्य हैं. इस फैसले का विरोध चंद विधायकों ने किया. पार्टी पर आजाद की पकड़ नहीं रह गई है. अब यह भी स्पष्ट हो गया कि उनकी इच्छा के विपरीत कई इंका विधायकों ने 'नवभारत टाइम्स' के पटना संस्करण के विरुद्ध विशेषाधिकार सूचना पर दस्तखत किए.

दरअसल आजाद के साथ समस्या यह है कि वे पार्टी के मिश्र, दुबे, तारिक अनवर, शिवचंद्र झा और केंद्रीय शिक्षा और संस्कृति राज्यमंत्री ललितेश्वर शाही सरीखे दिग्गजों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं. इन छह महीनों में पार्टी के असंतुष्ट तबके को भी जोड़े रखने की उनकी क्षमता को लेकर आलाकमान शंकालु हो उठा है. लेकिन आजाद को हटाने का फैसला लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके उत्तराधिकारी को असंतुष्ट बख्श ही देंगे. फिलहाल पार्टी के दिग्गजों ने आजाद का समर्थन करने का फैसला किया है. यह बात उस वक्त स्पष्ट हो गई जब राजीव ने असंतुष्टों से मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त केंद्रीय राज्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भेज दिया.

बिहार के इन असंतुष्टों को शायद इसलिए खामोश कर दिया गया क्योंकि इन में दुबे सरकार में रहे कई ऐसे नेता थे जिनकी अपनी छवि ही ठीक नहीं. लेकिन असंतुष्टों का अभियान सिरे चढ़ने से पहले ही नाकाम इसलिए हो गया क्योंकि आजाद ने अपना पक्ष मजबूत कर लिया था. प्रधानमंत्री से असंतुष्टों की मुलाकात के सिर्फ तीन दिन पहले ही उन्होंने राज्य की सर्वाधिक भ्रष्ट तीन सहकारी संस्थाओं—बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ (बिस्कोमान), बिहार राज्य भूमि विकास बैंक और बिहार राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्षों को बरखास्त कर दिया. विपक्ष भी लंबे अरसे से यह मांग कर रहा था.

सहकारी संस्थाओं में आमूल बदलाव का फैसला विपक्ष द्वारा खड़े किए गए 'भ्रष्टा-

कृष्णमुरारी किंगन

राज्य की सर्वाधिक तीन भ्रष्ट सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों को बरखास्त करने के लिए इंका आलाकमान ने मुख्यमंत्री आजाद की पीठ ठोंकी

सहकारी संस्थाओं के बरखास्त किए गए अध्यक्ष (ऊपर); और आजाद: सख्त रवैया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चार के हौवे' से निबटने की इंका की नीति के अनुरूप बैठता है. 'सहकारी संघों के बेताज बादशाहों'—बिस्कोमान के अध्यक्ष व इंका सांसद तपेश्वर सिंह, राज्य भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष व निर्दलीय विधायक राजो सिंह और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष व इंका विधायक एन.के. सिंह के खिलाफ बड़ी होशियार से कार्रवाई की गई.

हालांकि आलाकमान ने सफाई अभियान के लिए आजाद की पीठ ठोंकी लेकिन राज्य के कई इंकाइयों की प्रतिक्रिया भिन्न थी. एक विधायक का कहना था, "उन्हें यह भी करके देख लेने दो. चुनाव के वक्त सहकारी संघों का माफिया ही हमें पैसा और लठैत देता है. क्या हम उनकी मदद के बिना कुछ कर सकते हैं?" एक और विधायक ने कहा, "मतदान की देखरेख करने के लिए हम अरसे से मतदान केंद्र सहकारी माफिया के सुपुर्द करते आए हैं." एक और विधायक का मत था, "ऐसे कदम कार्यकाल के शुरू में उठाए जाने चाहिए न कि चुनाव से पहले."

आजाद जानते हैं कि ऐसे अभियान से सत्तारूढ़ दल के उन सदस्यों को ही नुकसान पहुंच सकता है जिन्होंने रसूख हासिल कर रखा है. सचाई तो यह है कि सहकारी संस्थाओं के कुछ पूर्व बोर्ड सदस्य आजाद के खासमखास थे और बरखास्तगी के चार दिन पहले मुख्यमंत्री ने उन्हें भोज पर भी आमंत्रित किया था. लेकिन उनके मुताबिक सहकारी माफिया केवल आधा दर्जन संसदीय क्षेत्रों के नतीजों पर ही असर डाल सकता है जबकि उनकी इस कार्रवाई से "बिहार में इंका के कम-से-कम 25 फीसदी वोट बढ़ गए हैं."

आजाद अब जान गए होंगे कि सूझबूझ से बनाई गई योजनाएं भी गड़बड़ा सकती हैं. आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि आजाद अभी बने रहेंगे लेकिन कई पार्टी सहयोगी उनकी छुट्टी करवाने को आमादा दिखते हैं. —फरजंद अहमद

बात पते की....कलमची

जनइच्छा सर्वोपरि

राजा मांडा, इलाहाबाद का शहंशाह, विपक्ष का मसीहा, देश की अंतरात्मा, तख्त का दावेदार—विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसे कई विशेषणों से अलंकृत किया जाता है. फर की अजीबोगरीब टोपी भी उनका एक पहचान चिन्ह है जिससे वे आधे गांधी और आधे चंगेज खां लगते हैं. लेकिन असली वी.पी. सिंह आखिर हैं कौन? इंका के आरोप के मुताबिक क्या वे औंधी खोपड़ी वाले हैं? अथवा जनमोर्चा की भविष्यवाणी के अनुसार भावी प्रधानमंत्री? या फिर लोगों की राय में उलझन में पड़े ऐसे शख्स जिन्हें अपनी मंजिल तक नहीं मालूम?

असलियत यह है कि वी.पी. सिंह अपनी स्थिति के बारे में एकदम स्पष्ट हैं. फर की टोपी पहनने के बावजूद वे ठंडे दिमाग और शांत स्वभाव के हैं. 'इलस्ट्रेटिव वीकली' के संपादक परस्तिश फंदी के साथ हाल ही में हुई उनकी बातचीत से तो यही लगा. बातचीत के अंश:

फंदी: आप यह अजीबोगरीब टोपी क्यों पहनते हैं?

वी.पी.: मेरे सिर पर यह गंजापन देख रहे हैं? यह बिलकुल राजीव जैसा ही है. इसे छिपाया इसलिए है कि लोग मुझे राजीव ही न समझ बैठें.

कार्टून अजीत नैनन

फंदी: पर लोग तो आप दोनों की तुलना कर ही रहे हैं.

वी.पी.: राजीव के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करना 'फेयर' (फैक्स) नहीं होगा. सरकार से 'बोफोर्स' किए जाने के बाद मैंने साफ कहा था कि मैं व्यक्तियों पर नहीं, मुद्दों पर आंदोलन छेड़ूंगा. मैं पश्चिम जर्मनी की पनडुब्बी जैसा नहीं हूं कि कभी तल पर तैरता नजर आऊं और कभी डुबकी लगा लूं. सवाल सिद्धांतों का है. बंटी हुई वफादारियों के साथ आप 'मिड्ल-मैन' नहीं हो सकते.

फंदी: इलाहाबाद का आपका चुनाव प्रचार तो व्यक्तियों पर आधारित था?

वी.पी.: वह अलग मामला है. लोग अब समझते हैं कि मुद्दा व्यक्तियों के टकराव का है. इससे पहले मुद्दों की राजनीति थी. मुझे लोगों की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ा. वे सर्वोपरि हैं.

फंदी: ठीक है! पर आपके बयान विरोधाभासी होते हैं. आप अपनी पक्की राय क्यों नहीं बनाते?

वी.पी.: इसमें हर्ज ही क्या है. सवाल तो इसकी व्याख्या का है. मसलन, मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता.

फंदी: आपने सरकारी ओहदा नहीं लेने की बात की थी?

वी.पी.: कही तो थी! मैं अभी भी कहता हूं कि मैं सरकारी ओहदा नहीं लेना चाहूंगा. पर सरकार ही अगर लोगों की हो जाए तो क्या किया जा सकता है?

फंदी: जनमोर्चा राजनैतिक पार्टी है या नहीं?

वी.पी.: यह भी व्याख्या का ही मामला है. कुछ लोग हमें राजनैतिक पार्टी बताते हैं तो कुछ लोग आंदोलन. इसमें कुछ गलत नहीं. देश को आंदोलन की जरूरत है. यहां राजनैतिक पार्टियां भी चाहिए ही. हम दोनों जरूरतें पूरी कर रहे हैं.

फंदी: आप लोग संसद से इस्तीफा देंगे या नहीं?

वी.पी.: हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई या तो भीतर से लड़ सकते हैं या बाहर से. यह बहुत टेढ़ा सवाल है. इसका फैसला हम लोगों पर छोड़ेंगे.

फंदी (चिढ़कर): आप किन लोगों की बात किए जा रहे हैं?

वी.पी.: मेरे लिए लोगों से तात्पर्य तो बिलकुल स्पष्ट है. मेरा मतलब है अरुण नेहरू, आरिफ, अजीत, देवीलाल....

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुजरात

रास हाथ में

मुख्यमंत्री चौधरी का ग्रहण टला

गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी बहुत खुशकिस्मत हैं. महीना भर पहले वे नाक में दम किए बैठे पार्टी असंतुष्टों से जूझ रहे थे. पर अब उनके होश दुरुस्त करके वे चैन की सांस ले रहे हैं. इंका आलाकमान भी इधर चौधरी की बातों को ही तरजीह देने लगा है.

इस भाग्य परिवर्तन के लिए चौधरी को दूसरे किस्म के बागियों का शुक्र-गुजार होना पड़ेगा. ये हैं राज्य के असंतुष्ट पुलिस-वाले, जिन्होंने पिछले महीने हड़ताल कर दी लेकिन बाद में सरकारी ताकत के आगे घुटने टेक दिए. हड़ताली पुलिसवालों के ड्यूटी पर लौटने और मुख्यमंत्री के सिर पर जीत का सेहरा बंधने से असंतुष्ट नेताओं का विद्रोही स्वर धीमा पड़ने लगा.

लेकिन चौधरी के हाथ मजबूत करने में सबसे ज्यादा योगदान पार्टी आकाओं के बदले हुए नजरिये का रहा. 1 अगस्त को चौधरी के विरोधी और प्रदेश इंका अध्यक्ष अहमद पटेल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें प्रेस तक ले जाने के लिए असंतुष्ट विधायकों की जमकर खिंचाई की. विधायकों का कसूर इतना ही था कि उन्होंने चौधरी को न हटाए जाने पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी. असंतुष्टों से जवाबतलब करते हुए पटेल ने सलाह दी, "अगर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कोई शिकायत है तो वह हमसे कहे. इसके लिए प्रेसवालों के पास जाने की जरूरत नहीं है."

इस आदेश से विधायकों—जीतेंद्र शाह और दिगंत ओझा की अगुआई वाले असंतुष्टों के खेमे में कुछ कदर मायूसी छा गई. इस खेमे को केंद्रीय योजनामंत्री माधव सिंह सोलंकी और पार्टी के वरिष्ठ नेता झीनाभाई दर्जी का समर्थन भी हासिल है. लेकिन चौधरी के खिलाफ रोष फिर भी बरकरार रहा. बागियों का मानना है कि राज्य सरकार केंद्र के भेजे अर्द्धसैनिक बलों और सेना की सहायता के बिना पुलिस विद्रोह पर काबू नहीं पा सकती थी. दिगंत ओझा गुस्से में कहते हैं, "अजीब बात है कि इस कामयाबी का पूरा श्रेय चौधरी ले रहे हैं."

इस बीच चौधरी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे रहे. पटेल के कदम से उत्साहित होकर वे पार्टी आलाकमान से सलाह-मशविरा करने दिल्ली रवाना हुए. केंद्र से उन्हें न सिर्फ समर्थन मिला बल्कि लगे हाथों उन्होंने अपने 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार करने की अनुमति भी पा ली. बताया जाता है कि राजीव गांधी ने उनसे 12 ऐसे विधायकों के नामों की सूची भी मांगी जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा. चौधरी यही चाहते भी थे. उन्होंने तुरंत यह सूची प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री शीला दीक्षित को थमा दी. पिछले पखवाड़े तक उन्हें वहां से हरी झंडी मिलने का इंतजार था. इससे चौधरी समर्थकों का हौसला बुलंद हो गया. वफादार खेमे के विधायक धीरूभाई दूधवाला कहते हैं, "हम जानते थे चौधरी बने रहेंगे और हमारा अनुमान सही निकला."

चौधरी के अपने दांवपेच भी उनके काम आए. वे दिल्ली में केंद्रीय इस्पात और खानमंत्री माखनलाल फोतेदार सरीखे प्रभावशाली पार्टी नेताओं का समर्थन जुटाने में कामयाब रहे. पिछले महीने फोतेदार जब गुजरात के दौरे पर आए तो कोई शक नहीं रहा कि चौधरी की पीठ पर उनका वरदहस्त है. प्रेस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में भी चौधरी ने मुस्तैदी दिखाई है. गुजराती के परस्पर विरोधी दो अखबार 'गुजरात समाचार' और 'संदेश' दोनों ही चौधरी के हिमायती माने जाते हैं.

असंतुष्टों के विरोध और उपचुनाव में पार्टी की हार के बावजूद ऐसे अनेक संयोगों की वजह से चौधरी ने कुर्सी बचा ली है. लेकिन उन्हें असंतुष्टों को फिलहाल झेलना ही होगा. वे तीन विरोधी मंत्रियों—शिक्षामंत्री हंसमुख पटेल, कृषिमंत्री महंत विजयदासजी और राजस्वमंत्री हरी सिंह महीदा—को निकाल पाएंगे, इसकी संभावना भी अब बहुत कम है. चौधरी के एक सहयोगी का कहना है, "अब चूंकि आम चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए चौधरी ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं कि उनके विभाग ही बदल दें."

इसके बावजूद चौधरी के हाथ अब ऐसा कारगर हथियार है जिसे वे जब चाहें असंतुष्टों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं. यह है मंत्रिमंडल का विस्तार करना. असंतुष्टों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं है और अगर उनमें से कुछ को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया तो विद्रोह के स्वर ठंडे पड़ते जाएंगे.

लेकिन फिलहाल असंतुष्टों का मानना है कि एक निकम्मे मुख्यमंत्री को अगर बने रहने दिया गया तो अगले चुनावों में इंका का सफाया तय है. लगता है पार्टी आलाकमान भी यह समझता है और इसी-लिए वह चौधरी के विरोधी अहमद पटेल को उन पर अंकुश लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. आलाकमान की रणनीति साफ है. वह कुछ अंदरूनी अंकुश लगाकर यथास्थिति बनाए रखना चाहता है. लेकिन अपनी ही रणनीति में अप्रत्याशित उलटफेर की उसकी आदत के कारण चौधरी शायद अभी भी चैन की नींद न सो पाएं.

—उदय माहूरकर

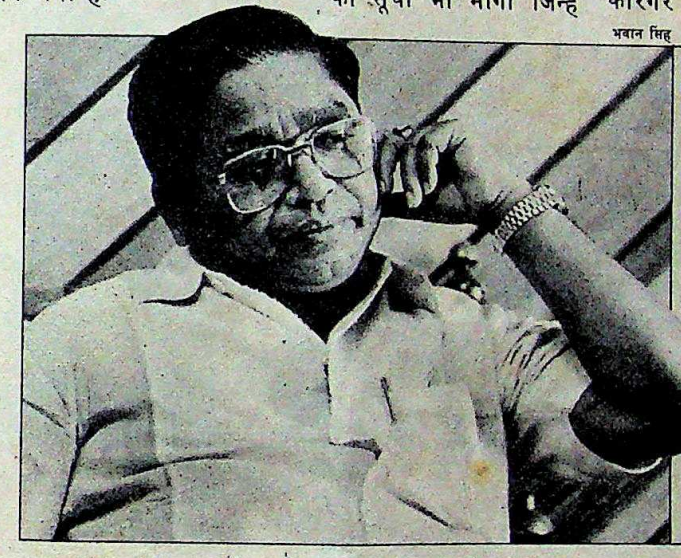

भवान सिंह

महीना भर पहले तक मुख्यमंत्री चौधरी पार्टी असंतुष्टों से जूझ रहे थे. पर अब उनके होश दुरुस्त करके वे चैन की सांस ले रहे हैं. इंका आलाकमान भी इधर चौधरी को तरजीह देने लगा है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लद्दाख

अनोखा उपहार

नेशनल कान्फ्रेंस को झटका

भारत के कठिनतम पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख के सबसे दुर्गम इलाकों में गिनी जाने वाली जांस्कार घाटी के लिए जुलाई के आखिरी दो सप्ताह ऐतिहासिक गहमागहमी के रहे. हेलीकॉप्टरों की पांतों और जीपों की काफिलों ने इस बेजान इलाके में मेले का जो अनूठा वातावरण पैदा किया वह न तो कभी यहां देखा गया और न उसकी कल्पना ही की जा सकती थी.

हालांकि इस मेले का मुख्य आकर्षण तिब्बत के पूर्व शासक और बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा थे जो वहां 'कालचक्र' समारोह के लिए धर्मशाला से आए थे. लेकिन 29 जुलाई के दिन केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने अचानक ही वहां पहुंचकर कुछ देर के लिए धार्मिक वातावरण पर ऐसी राजनैतिक छाप लगाई कि बूटा सिंह और राजीव गांधी जिंदाबाद के नारों ने 500 किमी दूर श्रीनगर में बैठे राजनैतिक दिग्गजों को भी झकझोर डाला.

शुक्रवार की सुबह लेह से आए चार सैनिक हेलीकॉप्टरों में से बूटा सिंह, केंद्रीय जल-भूतल परिवहन उपमंत्री और लद्दाख के इंकाई नेता पी. नामग्याल, ब्लैक कैट कमांडो का दस्ता और लद्दाखी बौद्ध नेता कुशक बकुला उतरे और देखते ही देखते 'कालचक्र' का धार्मिक वातावरण कुछ देर के लिए राजनीति की लपेट में आ गया. दलाई लामा के प्रवचन का मंच और लाउडस्पीकर भी मेहमानों को सौंप दिए गए. गृहमंत्री के लिए इससे बेहतर अवसर और नहीं हो सकता था कि उनकी बात सुनने के लिए लगभग 15 हजार लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो जाएं क्योंकि डेढ़ लाख की आबादी वाले और 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम आबादी वाले लद्दाख में इतना बड़ा समारोह कम ही हो पाता है.

भाषण की शुरुआत में ही बूटा सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि इस सभा में आना तो राजीव गांधी को था पर संसद में व्यस्तता के कारण उन्हें उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है. लेकिन राज्य सरकार में नेशनल कान्फ्रेंस के साथ इंका की भागीदारी होने के बावजूद सभा में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की गैरमौजूदगी का कारण जानने के लिए श्रोताओं को बूटा सिंह के भाषण के अंत तक इंतजार करना पड़ा. भाषण के अंतिम चरण में तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट और 'बूटा सिंह जिंदाबाद', 'राजीव गांधी जिंदाबाद' की गूंज के बीच उन्होंने घोषणा कर डाली कि पूरे लद्दाख क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने का फैसला कर लिया गया है और इसे मौजूदा संसद अधिवेशन के दौरान ही कानूनी जामा भी पहना दिया जाएगा. घोषणा के बाद बूटा सिंह कालचक्र मंडल के दर्शन करके और दलाई लामा से राजीव गांधी व अपने लिए पूजा का पवित्र 'खाताग' (रूमाल) तथा प्रसाद ग्रहण करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अपने पीछे ऐसा इंका समर्थक वातावरण छोड़ गए जो किसी नेशनल कान्फ्रेंस नेता की उपस्थिति में शायद ही बन पाता. शायद यही कारण था कि गृहमंत्री ने श्रीनगर के बजाय लेह का ही रास्ता चुना.

विजय क्रान्ति

दलाई लामा और बूटा सिंह: राजनैतिक प्रसाद

बूटा सिंह की घोषणा ने फारूक सरकार और लद्दाख के बीच घाटियों को और चौड़ा करने में कामयाबी हासिल कर ली है

गृहमंत्री की इस घोषणा ने लद्दाखी राजनीति में प्रसन्नता की नई लहर पैदा कर दी है. पिछले लगभग 15 साल से इस मांग के लिए चले आ रहे आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भिक्षु नेता और इन दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के सदस्य लामा लोबजंग की प्रतिक्रिया थी, "देर से ही सही पर आखिरकार लद्दाखी जनता की आवाज सुनी गई. अब लद्दाखी युवाओं को राष्ट्रीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में उनका वाजिब हिस्सा मिल सकेगा." कारगिल के युवा उपायुक्त फीरोज अहमद की टिप्पणी थी, "अब तक इस इलाके के विकास के लिए वही नियम और मानदंड अपनाए जा रहे थे जो आम तौर पर मैदानी इलाकों के हिसाब से तय किए जाते हैं. इलाके को नया दर्जा मिलने से अब यहां के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीतियां अपनाना संभव हो जाएगा."

दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कुछ साल पहले इसी तरह की घोषणा की थी पर धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के कारण राज्य सरकार ने इसे कभी सिरे नहीं चढ़ने दिया. बाद में दिसंबर 1984 में गुलशाह सरकार ने अपनी रजामंदी देकर यह रास्ता साफ किया. इसी दौरान राष्ट्रीय महापंजीयक ने अपने लघु सर्वेक्षण में भी लद्दाख अनुसूचित जनजाति चरित्र पर अपनी मुहर लगा दी है. इन बातों से आश्वस्त नामग्याल कहते हैं, "अगर किसी वजह से यह विधेयक वर्तमान अधिवेशन में पेश न किया जा सका तो सरकार अध्यादेश के रास्ते भी इसे लागू कर सकती है."

फैसला भले ही संसद के रास्ते लागू किया जाए या अध्यादेश के रास्ते, फिलहाल तो बूटा सिंह की घोषणा ने फारूक सरकार और लद्दाख के बीच घाटियों को और चौड़ा करने में कामयाबी हासिल कर ली है.

—विजय क्रान्ति, जांस्कार और कारगिल से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केरल

अपवित्र पापी

प्रेमिका की हत्या में मृत्युदंड

सत्ताइस वर्षीया खूबसूरत नर्स मेरीकुट्टी की हत्या के अभियोग में अंततः मुख्य अभियुक्त 49 वर्षीय फादर एंटोनी लाजर और उसके 'भाड़े के गुंडे' 30 वर्षीय नेल्सन उर्फ ससी को मृत्युदंड सुनाया गया. सात और अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा. क्विलोन के सत्र न्यायालय में इकट्ठा 5000 लोगों को यह फैसला लाउडस्पीकर से सुनाया गया.

यह मामला इसलिए सनसनीखेज बन गया था क्योंकि एक रोमन कैथोलिक पादरी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की थी. ईसाई मतावलंबियों की बहुसंख्या वाले केरल में मेरीकुट्टी के साथ फादर लाजर के अनुचित यौन संबंधों के रहस्योद्घाटन और उसकी हत्या से तहलका मच गया.

क्विलोन में चर्च द्वारा संचालित बोंजिगर अस्पताल में 1979 में नर्सिंग का प्रशिक्षण लेने के दरम्यान मेरीकुट्टी सबसे पहले लाजर से मिली थी. उस वक्त लाजर की देखरेख में अस्पताल का नया हिस्सा बन रहा था. जल्द ही दोनों प्यार की पींगें भरने लगे. लाजर ने अपने असर का इस्तेमाल कर उसे क्विलोन के नजदीक एक निजी अस्पताल में नौकरी दिलवा दी. बाद में लाजर ने अपने निवास के करीब चर्च द्वारा संचालित अस्पताल में मेरीकुट्टी को रखवा दिया. बदनामी की परवाह न करते हुए लाजर उसे यात्राओं में अपने साथ ले गया.

इस हादसे के बीज 1985 में उस वक्त पड़े जब मेरीकुट्टी ने लाजर से गुजारिश की कि वह चर्च से नाता तोड़कर उससे शादी कर ले. लेकिन लाजर ने उसे सलाह दी कि वह अपनी पसंद के किसी और शख्स से शादी कर ले ताकि वे अपने अवैध संबंध बरकरार रख सकें. मेरीकुट्टी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और अपनी शामत बुला ली. अगस्त 1985 में मेरीकुट्टी की शादी पेरावूर के लाजर मिरांडा से हो ही गई. हत्याकांड के फैसले में कहा गया है, "इससे फादर एंटोनी अनजाने में चोट खाए जहरीले सांप की भांति प्रतिशोध लेने की मुद्रा में आ गया."

मेरीकुट्टी के विवाह से पहले पादरी ने उससे एक ऐसे करार पर दस्तखत करा लिए थे जिसमें लिखा था कि उसने (मेरीकुट्टी ने) पादरी से 30,575 रु. ले रखे हैं. लाजर ने यह रकम मेरीकुट्टी को उसके परिवार की मदद की खातिर दी थी और अब वह इसका इस्तेमाल उसका उत्पीड़न करने के लिए कर रहा था. लाजर ने उसके खिलाफ एक दीवानी मामला दायर कर दिया और उसे गंभीर परिणामों की धमकी भी दे डाली.

चर्च के अधिकारियों से मेरीकुट्टी की शिकायत और पुलिस संरक्षण की मांग ने तो आग में जैसे घी का काम किया. पादरी ने साफ-साफ जता दिया कि वह उसे उसी

फादर एंटोनी लाजर (बीच में); और मेरीकुट्टी का चित्र (नीचे)

राजन पोद्दार

सूरत में बरुश सकता है जब वह फिर से उसका बिस्तर गरम करने लगे. लेकिन मां बन चुकी मेरीकुट्टी पादरी की बात मानने के मूड में नहीं थी. 13 अक्तूबर 1986 को ससी की अगुआई वाले लाजर के 'भाड़े के गुंडों' ने उसके घर में घुसकर उस पर हमला बोल दिया. विडंबना यह रही कि उसके पति ने उसी दिन सुबह स्थानीय पुलिस थाने में लाजर की धमकियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. मेरीकुट्टी को तुरंत त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई. मामले की जांच-पड़ताल कर रही अपराध शाखा ने 1987 में पादरी को मद्रास के एक अस्पताल में खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला इसलिए भी सनसनीखेज बन गया क्योंकि राज्य में यह तीसरा मौका था जब कोई पादरी सेक्स संबंधी हत्या में शामिल रहा है. 1966 और 1985 में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं. पादरियों के बढ़ते यौन अपराधों ने केरल के चर्च की नींव ही हिला दी है. पादरी टी. सत्यदास वट्टपरा कहते हैं, "ब्रह्मचर्य की बाध्यता की वजह से ही पादरियों में सेक्स अपराध बढ़ रहे हैं."

केरल का कोई भी चर्च, भले ही वह कैथोलिक हो अथवा प्रोटेस्टेंट, किसी में पैसे की कोई कमी नहीं है. हर साल विदेशी धार्मिक अनुदान एजेंसियों से करोड़ों रुपए चर्चों को मिलते हैं. और अब चर्च में नए अस्पताल, स्कूल और यहां तक कि व्यापारिक केंद्र भी बनवाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. इसकी वजह से तमाम पादरी ऐसी जीवनशैली अपना रहे हैं जो एकदम ईसाई धर्म के खिलाफ है.

केरल के कम-से-कम छह कैथोलिक पादरियों ने वेटिकन से शादी की 'विशेष अनुमति' देने और कैथोलिक संप्रदाय में बने रहने की अनुमति देने की प्रार्थना की है. लेकिन पोप जॉन पॉल (द्वितीय) ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है. पुलीकुन्नल चेतावनी देते हैं, "युवा पादरियों को शादी की मंजूरी देने के लिए केरल की आम जनता को चर्च के मुख्य पादरियों पर दबाव डालना चाहिए. वरना भविष्य में खासकर कैथोलिक चर्च को और भी गंभीर विवादों का सामना करना पड़ेगा." लाजर के मामले से मची सनसनी और धक्के के मद्देनजर तो यही लगता है कि केरल के चर्च को इस बात को पुख्ता करना होगा कि उनके पादरी किसी और नियम का उल्लंघन न करें.

—श्रीधर पिल्लै

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ललित सूरी पहुंच के बूते

घोटाले राजीव सरकार का पीछा नहीं छोड़ते लगते. बीफोर्स का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक और विवाद ने उसे घेर लिया है. खासी राजनैतिक पहुंच वाले दिल्ली के एक व्यापारी ललित सूरी पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के एक सौदे में जापान की सुमितोमो कार्पोरेशन से खासा कमीशन लेने का आरोप है. वरिष्ठ संपादक ***प्रभु चावला*** *ने बीसियों फाइलें टटोलकर और कई अधिकारियों से भेंट करके मामले के सारे सूत्र जोड़े. उनकी रिपोर्ट:*

प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए मानो अब यही कसर रह गई थी. पिछले पखवाड़े संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही वे एक और विवाद की जद में आ गए जिसमें उनके अंदरूनी हलके के सदस्य जुड़े हैं. अपने करीबी दोस्तों बच्चन बंधुओं और सतीश शर्मा को लेकर उन पर पहले ही पक्षपात के ऐसे आरोप हैं जो राजनैतिक तौर पर काफी महंगे साबित हुए हैं. अब आरोप दिल्ली के 41 वर्षीय व्यापारी ललित सूरी को लेकर है जिनका 1, रेसकोर्स रोड समेत कई आला हस्तियों से सीधा संपर्क है.

अंग्रेजी अखबार 'स्टेट्समैन' के पहले पेज पर छपे इन आरोपों के मुताबिक सूरी ने जापान की सुमितोमो कार्पोरेशन से 6.61 करोड़ रु. के कमीशन के बदले इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) से 100 करोड़ रु. का ठेका दिलवाने में मदद की.

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद 'स्टेट्समैन' की प्रतियां लहराते हुए सत्ताधारी दल से स्पष्टीकरण की मांग करने लगे. अखबार ने इस सौदे का पूरा ब्यौरा छापा था कि शुरू में लंदन के एक बैंक में जमा यह रकम सूरी भारत लाए थे. यह पखवाड़े की सबसे सनसनीखेज खबर थी. 'स्टेट्समैन' के मुताबिक सुमितोमो कार्पोरेशन ने सूरी की कंपनी ज्योत्स्ना होल्डिंग्स को 6.61 करोड़ रु. के कमीशन का भुगतान 11 किस्तों में किया. यह रकम लंदन के एक बैंक में पनामा की कंपनी एलजे इनकार-पोरेटेड के खातों में जमा कराई गई. रकम की आखिरी किस्त 1986 के अक्तूबर में अदा की गई. स्वैच्छिक घोषणा योजना के तहत, जिसकी अवधि वित्त मंत्रालय ने जून 1987 में तीन महीने के लिए और बढ़ा दी, यह रकम पिछले सितंबर में भारत लाई गई. ज्योत्स्ना होल्डिंग्स के मालिकों में सूरी की पत्नी ज्योत्स्ना और सास राजकुमारी नंदा का नाम दर्ज है. 1984 में सुमितोमो ने इस कंपनी को हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन को 100 करोड़ रु. के इस्पाती पाइप की आपूर्ति के लिए निविदाएं भरने में 'सलाह' देने की खातिर नियुक्त किया था. इस सौदे के लिए ओएनजीसी ने 1983 और 1984 में निविदाएं आमंत्रित कीं. समझौते की शर्तों के मुताबिक ज्योत्स्ना होल्डिंग्स को एक ठेके में 4.5 और दूसरे में 3.5 फीसदी कमीशन मिलना तय हुआ.

विपक्ष ने गंभीर सवाल यह उठाया कि सूरी में ऐसी क्या काबलियत थी कि उन्हें इतने नफीस काम के लिए सलाहकार बनाया गया. वे सतीश शर्मा के दोस्त माने जाते हैं और हाल तक शर्मा उनके किरायेदार थे. विपक्षी सांसदों का आरोप था कि प्रधानमंत्री के सहायक का करीबी होने नाते के सूरी को सलाहकार नियुक्त किया गया था. इन

भारत होटल्स परियोजना: बड़ों की कृपादृष्टि

भवान सिंह

प्रमोद पित्रेयार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पौ-बारह

सवालों के बीच वित्तमंत्री शंकरराव चव्हाण को परेशानी में यह भी मानना पड़ा कि इस सौदे में सुमितोमो को कोई बिचौलिया रखने की छूट नहीं दी गई थी. सरकार ने मामले की जांच का आश्वासन दिया.

पाइपलाइन की यह कहानी 1983 में शुरू हुई जब ओएनजीसी ने 300 करोड़ से भी ज्यादा के पाइपलाइन खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं. शुरू में तय हुआ कि इनकी आपूर्ति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) करेगा. पर 1983 के अंत में सेल के पाइपों को अनुपयुक्त पाया गया और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी की गईं. साल भर की बातचीत के बाद तरह-तरह के पाइपों की सप्लाई के लिए तीन कंपनियों—बर्गरोहर जीएमजीएच (पश्चिम जर्मनी), इंटरब्रास पेट्रोबास (ब्राजील) और सुमितोमो कार्पोरेशन (जापान) की एक सूची बनाई गई पर सौदा तय होने से पहले ही सुमितोमो ने ज्योत्स्ना होल्डिंग्स को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया. दो कंपनियों ने भी सलाहकार के तौर पर भारतीय फर्मों की सेवाएं लीं. इनमें एक कंपनी एक बड़े व्यापारिक घराने की है. प्रवर्तन एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या दूसरी दो भारतीय कंपनियों को भी विदेश में भुगतान किया गया?

लेकिन मुख्य मुद्दा सूरी के संपर्कों का है. प्रचार से दूर रहने वाले सूरी अचानक ही हर अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बन गए. खिचड़ी बालों वाले, गठीले और ऐयाश-से लगते सूरी दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके की एक भीतरी गली में 320 वर्गगज भूमि पर बने मकान में रहते हैं और दो सीटों वाली मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार चलाते हैं.

कानूनी तौर पर सूरी हालांकि पाक-साफ हैं क्योंकि उन्होंने यह आमदनी घोषित करके इस पर तीन करोड़ रु. से अधिक आयकर भी जमा करा दिया है मगर वे इस रकम को एक साल से ज्यादा अरसे तक विदेश में रखने की वजह नहीं बता सके. बहरहाल आयकर विभाग ने उन्हें ब्याज से मुक्त करते हुए आमदनी का ब्यौरा देने में हुई देरी के लिए भी माफ कर दिया. यहां तक कि चव्हाण ने भी संसद में माना कि "पहली नजर में देखें तो इसमें विदेशी मुद्रा विनिमय कानून का उल्लंघन हुआ है. इसीलिए जब हम सभी पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है और इसमें कानूनी कार्रवाई की जरूरत है, तभी कार्रवाई की जाएगी."

साफ है कि सरकार बचाव कर रही थी. सौदे के सिलसिले में कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं. मसलन

आरोप लगाया गया है कि ललित सूरी ने जापान की कंपनी सुमितोमो कार्पोरेशन से 6.61 करोड़ रुपए के कमीशन के बदले इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से 100 करोड़ का ठेका दिलवाने में सहायता की

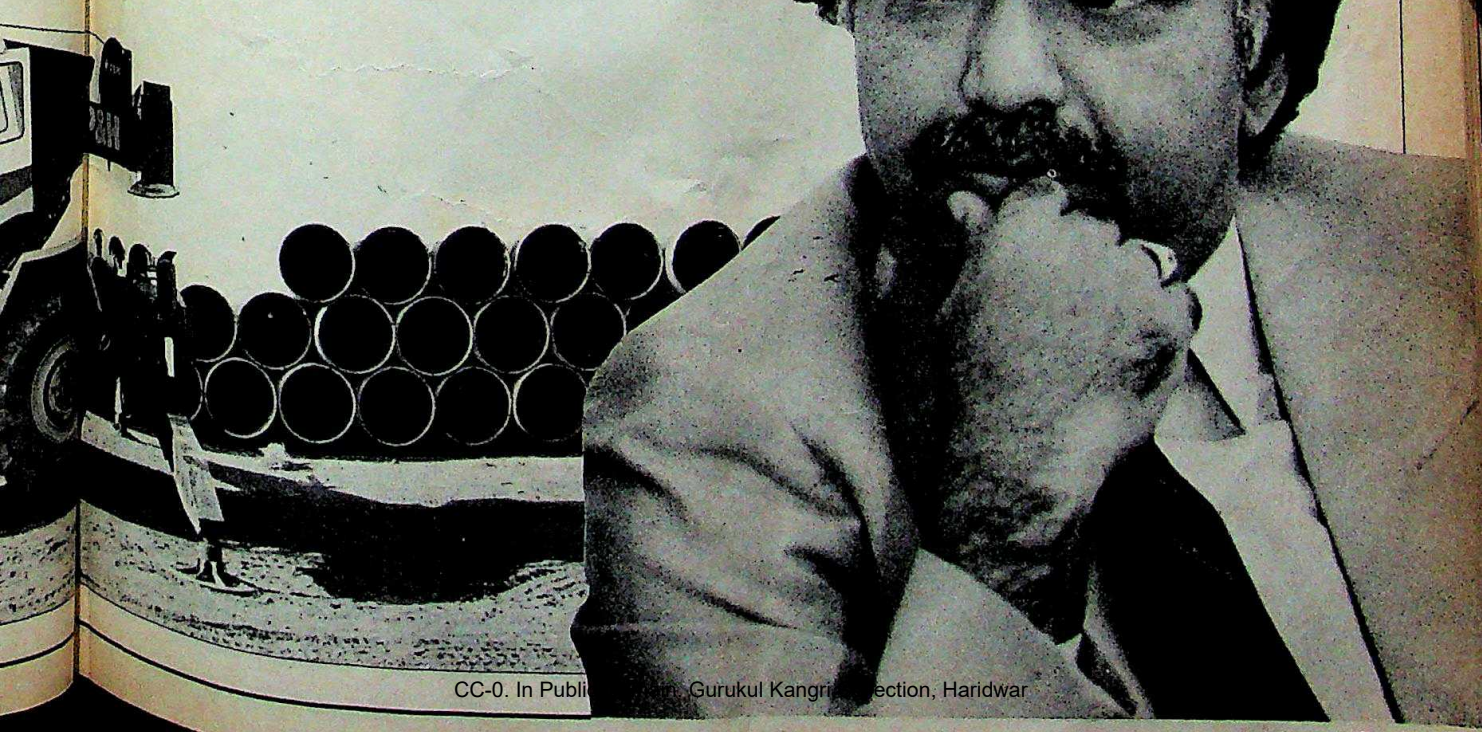

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

► सुमितोमो ने ज्योत्स्ना होल्डिंग्स को सलाहकार क्यों बनाया?

► सरकार को पता क्यों नहीं चला कि सौदे में बिचौलिए की हैसियत से कुछ भारतीय शामिल हैं?

► पैसा एक साल से भी ज्यादा अरसे तक विदेश में क्यों रखा गया?

► एलजे इनकारपोरेटेड का मालिक कौन है?

पर वित्त राज्यमंत्री बी.के. गढ़वी ने घोषणा की कि सूरी ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है क्योंकि सितंबर में उन्होंने सारा पैसा सामान्य तरीके से बैंकों के जरिये भारत वापस लाया. सूरी कहते हैं, "मेरे बही-खातों की कोई भी जांच कर सकता है. पैसे-पैसे का हिसाब है और उसके लिए आयकर चुकाया गया है." वित्त मंत्रालय को दी सफाई में सूरी ने दावा किया है कि ज्योत्स्ना होल्डिंग्स और सुमितोमो के बीच हुए समझौते के मुताबिक सूरी लंदन के बैंक में सुमितोमो द्वारा जमा किया गया पैसा तब तक नहीं निकाल सकते थे जब तक पूरा सौदा निबट नहीं जाता और सुमितोमो को भारत सरकार से पूरे पैसे नहीं मिल जाते. यह पैसा लंबित खाते में डाल दिया गया. रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना ऐसा करना विदेशी मुद्रा नियमन कानून का उल्लंघन है.

अपने बचाव में सूरी यह भी कहते हैं कि अगस्त 1987 में हुए अंतिम भुगतान के एक महीने बाद ही पैसा भारत ले आया गया. उनके समर्थक भी कहते हैं कि वे उन थोड़े-से भारतीयों में से हैं जो विदेशी मुद्रा को भारत में ले आए. सूरी का दावा है कि दिल्ली ऑटोमोबाइल्स के काम में शामिल रहने की वजह से वे इस्पाती ढांचे बनाने के माहिर हैं, "मुझे स्टील के काम की पूरी जानकारी है."

उनके इतने बचाव के बावजूद अटकलें जारी हैं. जैसे यह पता लगने के बाद कि सुमितोमो दोहरे कर से बचने के लिए ज्योत्स्ना को दिए भुगतान की जानकारी भारत सरकार को देने जा रही है, इससे पहले ही सूरी पैसा हिंदुस्तान ले आए. पर भारत सरकार और सुमितोमो दोनों ही इसका खंडन करती हैं. पैसा भारत ले जाने की एक और वजह भी हो सकती है. वह यह कि सूरी को भारत होटल्स के बहुमत शेयर खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी. वे होटल पर नियंत्रण के लिए अपने बड़े भाई गंगासागर सूरी के साथ घिनौने पारिवारिक विवाद में फंसे हुए हैं. पैसा आने के एक महीने बाद कनाट प्लेस की होटल परियोजना 'हॉलीडे इन क्राउन प्लाजा' में लगा दिया गया.

पर सूरी परिवार के लिए सबसे बुरी बात यह रही कि गांधी परिवार से उनके अरसे से चल रहे रिश्ते भी जगजाहिर हो गए. जाहिर है कि उनके विभिन्न धंधों की पौ-बारह होने में इन रिश्तों से काफी मदद मिली. 'स्टेट्समैन' की खबर के कुछ ही दिन बाद एक और भंडाफोड़ हुआ. पता चला कि उनके बड़े भाई रमेश ने 1985 में कंप्यूटरों के एक सौदे में 1.5 करोड़ रु. का कमीशन लिया था. 60 करोड़ रु. के कंप्यूटरों का यह सौदा जापान की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन (एनईसी) और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बीच हुआ था.

इससे पहले 70 करोड़ रु. की 550 कमरों वाली भारत होटल्स परियोजना के सिलसिले में कई असुविधाजनक सवाल उठ चुके हैं. इमरजेंसी में गंगासागर द्वारा शुरू की गई इस परियोजना के मालिक अब ललित और रमेश हैं. सूरी बंधु संजय गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे. दो साल बाद जनता सरकार ने इस होटल की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया. सूरी परिवार ने अदालत की शरण ली और अंततः 1980 में इंका के सत्ता में लौटने पर उन्हें होटल की यह जमीन वापस मिली. सरकार ने परियोजना को हरी झंडी दिखाकर उदार आयात लाइसेंसों के अलावा वित्तीय मदद भी दी. शर्त बस यह थी कि इसे 1982 के एशियाई खेलों से पहले तैयार हो जाना चाहिए. पर परियोजना अभी तक अधूरी है और वित्तीय संस्थानों को 28 करोड़ रु. से भी ज्यादा के उन कर्जों

भवान सिंह

गांधी परिवार से रिश्तों की वजह से ही सागर सूरी ने दिल्ली के उस खास इलाके में सबसे ऊंची इमारत बनाने की इजाजत पा ली जहां किसी को तिमंजिली इमारत भी बनाने नहीं दिया गया था

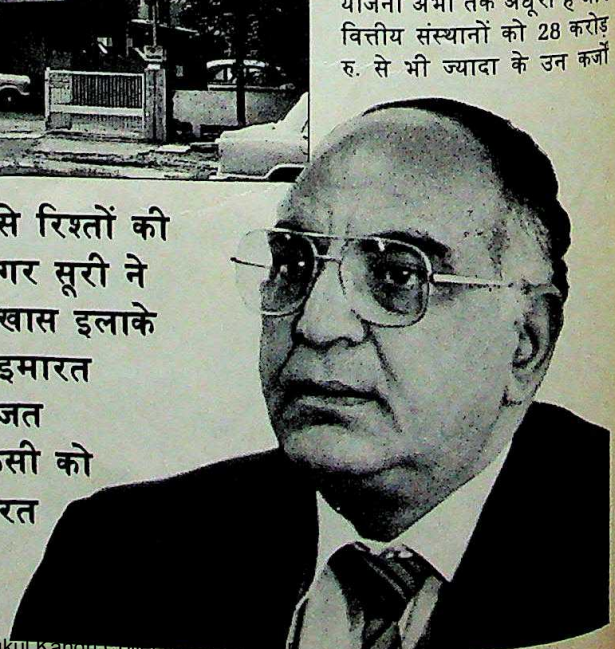

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का समय बढ़ाना पड़ा जिनका तीन साल पहले ही भुगतान हो जाना चाहिए था.

होटलों में लगाई गई रकम के लिए ज्यादातर पैसा या तो वित्तीय संस्थानों से लिया गया या विदेशों से आया. मसलन ज्योत्स्ना होल्डिंग्स ने एलजे इनकारपोरेटेड को 1.80 करोड़ रु. से अधिक के शेयर बेचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की इजाजत ली. एलजे एक आप्रवासी भारतीय की कंपनी है जो भारत होटल्स लि. की एक छोटी हिस्सेदार बन गई. कंपनी दीक्षा होल्डिंग्स प्रा.लि. ने रूस को चावल सप्लाई के सौदे से पिछले चार साल में आठ करोड़ रु. कमाए. रूसी सौदे चूंकि अक्सर पार्टी के लिए पैसा उगाहने वालों द्वारा आला राजनैतिक संपर्क वाले लोगों को ही दिए जाते हैं इसलिए माना जाता है कि सूरी को यह सौदा 1983 में अरुण नेहरू ने दिलवाया होगा.

इतना ही नहीं, दो महीने पहले रमेश को गाजियाबाद जिले का एकमात्र मारुति वितरक नियुक्त किया गया. दरअसल जब भी सूरी परिवार का मामला आया, मारुति उद्योग लिमिटेड ने काफी उदार रवैया अख्तियार किया. संजय गांधी और बाद में राजीव गांधी से गंगासागर के करीबी रिश्तों की वजह से उनके बेटे अश्विनी को 1985 में मारुति के दो में से एक वितरक के तौर पर चुना गया. अश्विनी को वितरक चुनते समय मारुति उद्योग ने अपनी इस शर्त को भी नजरअंदाज किया कि जो किसी दूसरी कार के वितरक हैं, वे नहीं चुने जाएंगे. गंगासागर नई दिल्ली और हरियाणा में प्रीमियर पद्मिनी कार के वितरक हैं. एक साल बाद मारुति वालों ने ललित के ससुराल नंदा परिवार को अहमदाबाद के लिए मारुति का वितरक बना दिया. हाल ही में सूरी ने मारुति कार में एयर कंडीशनर लगाने की एक इकाई उत्तर प्रदेश में खोली है.

अगर ललित और रमेश को सरकारी वरदहस्त मिला तो गंगासागर भी पीछे नहीं रहे. गंगासागर की मिल्कियत वाली दिल्ली ऑटो ऐंड फाइनेंस कंपनी को 1983 में जीपें खरीदने के लिए बैंकों ने विशेष कर्जे दिए. इन्हीं जीपों का इस्तेमाल 1983 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में इंका ने किया.

गांधी परिवार से रिश्तों की वजह से ही गंगासागर ने दिल्ली के खास इलाके तिलक मार्ग पर सबसे ऊंची आवासीय इमारत, 10 मंजिला सूरी अपार्टमेंट बनाने की इजाजत हासिल कर ली. तब तक इस सड़क पर किसी को तीन मंजिली इमारत बनाने की भी इजाजत नहीं दी गई थी. कई राजनैतिक और वरिष्ठ सरकारी अफसर ही नहीं, खुद संजय गांधी भी इस इमारत में फ्लैट लेने वालों में थे. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार गंगासागर को गाजियाबाद में एक खास किस्म का फार्म हाउस बनाने की इजाजत दी, हालांकि इससे स्थानीय भूमि कानून का उल्लंघन होता था.

सूरी बंधुओं की कामयाबी की कहानी रंक से राजा बनने की कथा है. बीस साल पहले वे फिएट कारें बेचने और बसों के ढांचे बनाने का छोटा-मोटा धंधा करते थे. पर आज तीनों सूरी बंधुओं ने सामाजिक और राजनैतिक हलकों में बहुचर्चित होकर बच्चन बंधुओं की जगह ले ली है. शायद ही कोई ऐसा मंत्री या इंकाई मुख्यमंत्री हो जो उनके पास न जाता हो या उनसे दुआ-सलाम न रखता हो. जब सूरी बंधुओं के व्यापारिक मामलों को हरी झंडी दिखाने का वक्त आता है, औपचारिकताओं के मामले में सरकारी अफसर तो क्या, बड़े-बड़े नेता तक ढीले पड़ जाते हैं.

दरअसल, बंटवारे के दौरान रावलपिंडी से दिल्ली आए ये तीनों शरणार्थी बंधु इस समय दिल्ली के सबसे रईस पंजाबियों में शुमार हैं, जिनके पास करीब 200 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है. वे मारुति कारों का धंधा करते हैं, बसों के ढांचे बनाते हैं, होटल चलाते हैं और अचल संपत्ति का कारोबार करते हैं.

इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी कामयाबी में उनकी कुशलता और लगन का योगदान तो है ही, पर भारत के शासक परिवार के लगातार सहयोग की वजह से ही उनके सितारे इस कदर चमके हैं.

भवान सिंह

संजय गांधी के बाद राजीव गांधी से भी गंगासागर सूरी के करीबी रिश्तों के कारण उनके बेटे अश्विनी सूरी को 1985 में मारुति कारों के दो में से एक वितरक के तौर पर चुन लिया गया

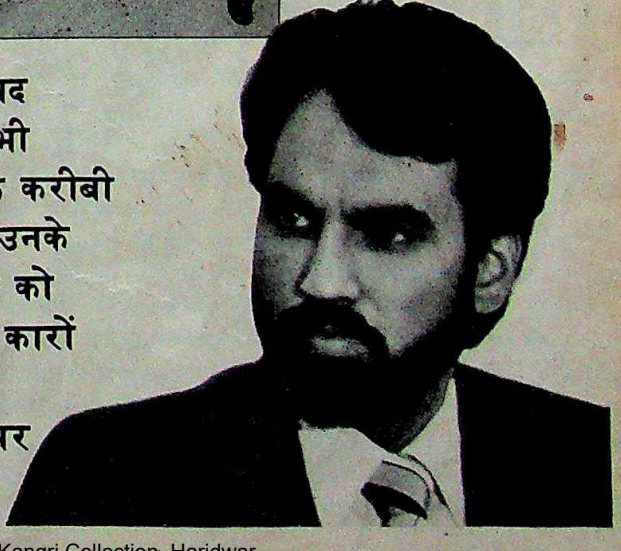

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खराब अतीत, बिगड़ा भविष्य

अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में वायुदूत की उड़ानों का विस्तार करने की मोतीलाल वोरा की लंबी-चौड़ी योजना धरी की धरी रह गई. कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री से नागरिक उड्डयन मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार छिन गया. पर उनका सहारा छिनने से पहले ही मध्य प्रदेश में वायुदूत की सेवाएं खराब रही हैं. उड़ानों में अक्सर देरी होती या वे अचानक ही स्थगित कर दी जातीं. 'नियमित' उड़ानें भी काफी अनियमित रहने लगी थीं.

सुविधाएं मुहैया कराने के घटिया तंत्र को देखते हुए यह कोई हैरत की बात नहीं. बिलासपुर हवाई अड्डे पर खुलेआम जानवर चरते रहते हैं. उसमें टेलीफोन तक नहीं है. कमजोर सुरक्षा व्यवस्था की वजह से चालक दल के लोग वहां वैसे ही घबराए रहते हैं. महीने भर पहले एक इंका नेता ने जब उन पर छोटे-से डोर्नियर विमान में अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को ओवरलोड करके ले जाने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने विमान उड़ाने से ही इनकार कर दिया था.

आर.सी. साह

उद्घाटन उड़ान भर कर लौटे वोरा: मजेदार वाकये

इतनी ही मजेदार बात सतना की उद्घाटन उड़ान के दौरान हुई. वोरा, वायुदूत अधिकारियों और कुछ पत्रकारों को लेकर जब यह विमान उड़ा तो चालक दल रास्ता ही भूल गया. आखिर जब एक पत्रकार ने चूना-पत्थर की भट्टियों पर से उड़ते हुए धूल के बादल देखे तो उसने सतना से 70 किलोमीटर दूर की तहसील मैहर को पहचाना. वहां से पायलट रेल पटरियों के सहारे सतना पहुंचा. और उधर बस्तर के वनवासी इलाके जगदलपुर से उद्घाटन उड़ान का विमान अभी कुछ ऊपर पहुंचा ही था कि एक ब्रीफकेस छिटककर बाहर जा गिरा. यह घटना अपने आप में हालांकि काफी अनोखी थी पर वायुदूत के कामकाज की यह छोटी-सी मिसाल है.

ताकि पोल न खुल जाए

गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी पुलिस के निचले तबके के कर्मचारियों को अनुशासित करने में भले ही सफल हो गए हों, पर बड़ों में नाराजगी कायम है. नाराजगी पुलिस आंदोलन को दबाने की कार्रवाई को लेकर है. चौधरी को तो इससे राजनैतिक फायदा ही मिला. लेकिन पुलिस महानिदेशक एम.एम. सिंह ने राज्य सचिव को एक कड़ी चिट्ठी लिखी है जिसमें अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त एस.एन. सिन्हा पर आरोप लगाया गया है कि आंदोलन को दबाने के अभियान के दौरान उन्होंने आदेशों का उल्लंघन किया. चौधरी के दुलारे अधिकारी सिन्हा पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं. सिंह एक सख्त और खरे पुलिस अधिकारी के रूप में विख्यात हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि सिन्हा के व्यवहार से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी. पुलिस आयुक्त पर यह आरोप भी है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने पुलिस महानिदेशक के साथ दुर्व्यवहार किया.

एम.एम. सिंह

एस.एन. सिन्हा

बात इतनी बढ़ गई थी कि सिंह के दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पास बुलाया और आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर गृहमंत्री बूटा सिंह से कुछ न कहें. चौधरी को डर था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के जिस दावे पर वे टिके हुए हैं, सिंह के मुंह खोलने पर उसकी ही पोल खुल जाएगी. और विडंबना यह कि कानून और व्यवस्था में सुधार के लिए चौधरी दोनों पुलिस अधिकारियों—सिंह और सिन्हा—के ऋणी हैं. लेकिन चौधरी अपने द्वारा नाराज किए हुए लोगों का मुंह बंद किए रखने में कब तक कामयाब होते रहेंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

हुक्काम जब गरियाते हैं....

पिछले महीने इंका विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी का पारा जब सार्वजनिक तौर पर सातवें आसमान पर पहुंचा तो गरीबों के मसीहा वाली पार्टी की छवि दांव पर लग गई. सोलंकी उस समय काफी परेशान हो उठे जब ग्रामसभा चुनाव के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर में उनके 12 समर्थक हिरासत में ले लिए गए. उन पर कक्कोद पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ने वाले दो निर्वाचन केंद्रों से छह मतपेटियां उठा ले जाने का आरोप था. सोलंकी ने उनको रिहा कराने के लिए जिले के अधिकारियों पर दबाव भी डाला. पर वे नहीं माने.

एकदम गुस्से में आकर सोलंकी अतिरिक्त जिलाधीश कोमल राम के बंगले पर जा धमके, जहां मामले पर बातचीत चल रही थी. वे वहां कोमल राम, डीएसपी उदय प्रताप और सब-इंस्पेक्टर माला रानी (संबंधित थाने के प्रभारी) पर बरस पड़े, "मैं कोक्कद पुलिस थाने पर प्रदर्शन करवाकर वहां आग लगवा दूंगा—मैं जल्दी ही गृहमंत्री बनकर तुम सबको बरखास्त कर दूंगा." इन लोगों की जाति और चरित्र पर उनकी टिप्पणियां तो और भी काबिले एतराज थीं, "मैंने बहुत से आईएएस अफसरों को (नेताओं के) पांव पड़ते देखा है. मैं हरिजन अफसरों की औकात जानता हूं. मुझे पता है वे इम्तहान कैसे पास करते हैं." कोमल राम और उदय प्रताप दोनों हरिजन हैं.

सोलंकी: अशोभनीय

सोलंकी के इस प्रकोप के बाद माला रानी ने तुरंत विधायक के 'असभ्य' और 'धमकीपूर्ण' रवैये के खिलाफ इस्तीफा दे दिया. उदय प्रताप ने भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी और सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इस्तीफे की पेशकश की. उधर कोमल राम ने भी अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेज दी. पर सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है. वजह यह है कि मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई करके ठाकुर लॉबी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जन्मदिन पर उमड़ा प्रेम

पिछले पखवाड़े जब केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरन ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया तो उन्हें बधाई देने वालों में आगे कौन था? इंका के राजनैतिक दुश्मन नंबर एक, मौजूदा मुख्यमंत्री 69 वर्षीय ई.के. नयनार. नयनार ने अपने इस विरोधी नेता के बारे में बहुत भावुक होकर कहा, "50 वर्ष से भी पहले की बात है जब हम दोनों कन्नानूर के एक गांव से राजनीति के क्षेत्र में उतरे थे. हमने राजनीति का अलग-अलग रास्ता चुना लेकिन उद्देश्य

राजन पोद्दार

नयनार (बाएं) और करुणाकरन: भावना का उफान

एक ही था—राज्य और देश की जनता की सेवा करना."

मूल्यों और आदर्शों के प्रति पुरानी पीढ़ी की निष्ठा के बारे में नयनार ने कहा, "करुणाकरन कई अर्थों में पक्के गांधीवादी हैं." जवाब में करुणाकरन ने कहा, "जन आंदोलन और ईश्वर में आस्था के कारण ही मैं आज यहां तक पहुंचा हूं." बाद में राज्यपाल रामदुलारी सिन्हा के यहां आयोजित एक भोज में विधानसभा अध्यक्ष वर्कला राधाकृष्णन ने कहा, "जब तक करुणाकरन केरल में हैं, यहां सक्रियता बनी रहेगी." इस बीच करुणाकरन और उनकी पार्टी नयनार का 70वां जन्मदिन जिस पैमाने पर मनाने की योजना बना रही है, उसकी शायद माकपा कल्पना भी नहीं कर पाएगी.

कुलपति के आदेश से सदमा

पांडिचेरी के केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े सालिम अली स्कूल ऑफ इकॉलॉजी का माहौल पिछले पखवाड़े बहुत गरम था. इसका कारण था कुलपति के. वेंकटसुब्रमण्यम द्वारा विश्वप्रसिद्ध पर्यावरणविद और मानद डीन वी.एम. मेहरोमजी और सालिम अली के रिश्तेदार, प्रमुख विद्वान तथा एडजंक्ट प्रोफेसर रऊफ अली को हटाने का आदेश. 59 वर्षीय मेहरोमजी ने वर्षों की मेहनत के बाद भारत का वनस्पति संबंधी नक्शा तैयार किया है. मजेदार बात यह है कि विश्वविद्यालय इन्हीं दो नामों का उल्लेख करता रहा है. इसलिए जब कुलपति ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी आदमी मानद डीन और एडजंक्ट प्रोफेसर के पद पर एक वर्ष से अधिक तक नहीं रह सकता, तो कइयों को सदमा लगा.

चाफेकर

संस्था छोड़ने के पहले मेहरोमजी के द्वारा पीएचडी कोर्स के लिए चयनित तीन अंशकालिक उम्मीदवारों को हटा दिया गया. संस्था के जानकार लोगों का कहना है कि कुलपति वेंकटसुब्रमण्यम अपने एक रिश्तेदार के.वी. देवीप्रसाद को इस पद के लिए तैयार कर रहे हैं जिन्होंने विकास पदाधिकारी के रूप में काम शुरू किया और जो अभी रीडर हैं. वैसे अभी डीन का पद एस.वी. चाफेकर को दिया गया है. लेकिन कुलपति आरोपों से परेशान नहीं हैं. वे कहते हैं, "उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता था. हां, वे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आते रहेंगे." बहरहाल, नुकसान तो विश्वविद्यालय का ही हुआ है.

कभी साथी थे, अब चुनौती हैं

लगता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव के लिए उनके पूर्व मंत्री लगातार परेशानी का कारण बने रहेंगे. पिछले महीने पूर्व आबकारीमंत्री मुद्रागदा पद्मनाभम ने मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने रामराव को चुनौती दी कि वे प्रतिपाडु विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भिड़कर देख लें. पद्मनाभम ने 28 मार्च को तेलुगु देशम छोड़ने के साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था.

पद्मनाभम

पद्मनाभम अब एक क्षेत्रीय दल बनाना चाहते हैं. इंका ने भी अपने कुछ छुटभैयों को कहा है कि वे कापू, तेलगा, बलीजा और ओंटारी जातियों के लोगों को उकसाएं ताकि वे पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग पर पद्मनाभम के आंदोलन को तेज करें. इन जातियों की आबादी राज्य का पांचवां हिस्सा है. उकसाने के काम में विजयवाड़ा के विवादास्पद इंका विधायक वी. मोहन रंगराव को भी लगाया गया है.

उधर, इंका मांग कर रही है कि रामराव के ऊपर पद्मनाभम ने जो आरोप लगाए हैं उनसे संबंधित फाइलें विधानसभा में रखी जाएं. पर सरकार के सहमत होने से लगता है मामला फिस्स हो जाएगा.

अच्छे सपने बुरे सपने

नंदिनी सतपथी के सपने मानो साकार हो उठे, पर ओडीसा के मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक के लिए यह दुःस्वप्न ही था. पिछले पखवाड़े सतपथी की इंका में वापसी उनकी एक दशक पुरानी कोशिशों का ही फल था. पर राज्य में आठ साल तक बेखौफ बादशाहत करने वाले पटनायक के दिल में इससे खौफ समा गया है.

नंदिनी

सतपथी को फिर से पार्टी में लेने का विरोध करने में राज्य पार्टी अध्यक्ष केलुचरण लेंका भी उनके साथ रहे हैं. अगर सतपथी तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बन गईं तो यह उनेक उतार-चढ़ाव वाले राजनैतिक जीवन में एक और मील का पत्थर होगा. वामपंथी छात्र आंदोलन की कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करके वे '60 के दशक में कांग्रेस में शामिल हुईं. 1972 में वे मुख्यमंत्री बनीं और 1974 में (भाकपा की मदद से) उन्होंने फिर इस पद की शपथ ली. इमरजेंसी के बाद वे जपा में शामिल हो गईं. 1980 के चुनावों में जनता पार्टी के मात खाने के बाद उन्होंने कांग्रेस (स) का दामन पकड़ा. फिर इंका में पहुंचने की आस में उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई भंग कर दी. पर उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले आड़े आ गए. तब सतपथी ने 1985 में 'जागृत ओडीसा' नाम से क्षेत्रीय पार्टी बना डाली. वैसे सतपथी के लिए मैदान अभी भी खुला पड़ा है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक रैली में करुणानिधिः मुद्दे उठाने और चंदा बटोरने की होड़

तमिलनाडु

तुरुप के पत्ते की चाल

चुनाव की संभावना से वोट बटोरने की इंका की तैयारियां

प्रधानमंत्री राजीव गांधी पिछले पखवाड़े तमिलनाडु में जनता से घुलने-मिलने में व्यस्त रहे. उनके इस दौरे से यह साफ हो गया कि राज्य में दौरे का असल मकसद है आगामी चुनाव के लिए वोट बटोरने की जमीन तैयार करना. वरिष्ठ संपादक **प्रभु चावला** *राज्य की राजनैतिक स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं:*

आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत की संभावनाएं प्रबल होती देख प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस दक्षिणी राज्य को खास अहमियत देनी शुरू कर दी है. पिछले तीन महीनों में उन्होंने इस राज्य का तीन बार दौरा किया. इस बार तीन दिन के तूफानी दौरे में उन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का जैसे श्रीगणेश ही कर दिया.

हालांकि इसे सरकारी यात्रा बताया गया लेकिन इसके पीछे मंशा छिपाए न छिप सकी. अपनी पसंदीदा जीप में अपनी पत्नी सोनिया गांधी को बगल में बिठाए उन्होंने इस राज्य के मुख्यतः ग्रामीण इलाकों की करीब 700 किमी कच्ची-पक्की सड़कों को नाप डाला. चुनावी गणित के अनुसार उन्होंने तीन जिलों के तकरीबन 25 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया.

वैसे, इस मुहिम की सफलता संदिग्ध ही दिखती है क्योंकि पिछले दो दशकों से तमिल मतदाताओं ने इंका को गद्दीनशीन होने का मौका नहीं दिया है. फिर भी, राजीव और उनकी पार्टी इस बार मतदाताओं का रुख भांपने की कोशिश कर रही है. राष्ट्रपति

तमिलनाडु

अनूठा शाही दौरा

राजीव का जनसंपर्क अभियान

राजीव गांधी की 'शाही सवारी' हमेशा तामझाम भरी होती है. किसी धूल-धूसरित गांव में उतरते हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही तेजरफ्तार जीप के पीछे-पीछे चलती कारों का पिछड़ता हुआ काफिला, रास्ते भर दोनों ओर रंग-बिरंगे कपड़ों में लोगों की भीड़, या जनसभाओं में छुट्टी के दिन जैसा माहौल. और इन सबसे बढ़कर नाटकीय होता है उस जगह का चुनाव जिसकी मंजूरी प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के चुनावी भविष्य को ध्यान में रखकर देते हैं.

तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही पिछले पखवाड़े सफेद लुंगी पहने राजीव गांधी ने राज्य के ग्रामीण इलाकों का तीन दिन का दौरा किया. यहां की धर्मभीरू जनता का दिल जीतने के लिए उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले सारे मंदिरों में दर्शन-पूजा भी की. इसके कारण कुछ जनसभाओं में उनके पहुंचने में देरी भी हुई.

लेकिन यह दौरा ठेठ 'राजीव गति' से हुआ. उन्होंने तीन दिन में 643 किलोमीटर की दूरी तय की. राजीव यहां भी जीप से चले और वक्त बचाने के लिए गाड़ी में ही काजू या सैंडविच खा लेते. लेकिन उनके साथ चल रही 50 कारों पर सवार लोगों को तेज धूप में सिर खपाना पड़ा.

राजनैतिक शब्दावली में कहें तो इस पूरे अभियान का मतलब खुद राजीव और इंका का मनोबल बढ़ाना था. दक्षिण आर्कोट, तंजावुर और तिरुचि जिले ही इस यात्रा के केंद्र थे. राजीव सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते जा रहे थे और जहां-तहां रुककर जल्दबाजी में बनी कामराज या इंदिरा गांधी की मूर्तियों का अनावरण भी करते जाते. सांसद और तमिलनाडु इंका के महासचिव रंगराजन कुमारमंगलम मानते हैं, "कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां दो दिन पहले ही मूर्तियां लगाई गई थीं. वजह यह थी कि प्रधानमंत्री के वहां रुकने के बारे में सहमति हमने आखिरी वक्त में दी."

तीन जिलों के दौरे में राजीव ने 103

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गांवों और कस्बों में रुककर आरती उतरवाई और स्वागत समारोहों में भाषण दिए. हर जगह काफी भीड़ जुटी और लोगों ने जोशखरोश से उनका स्वागत किया.

लेकिन हर जगह दुलार ही नहीं मिला. तिरुचि जिले के तिरुमनुर गांव के बाहर राजीव एकाएक एक महिला मजदूर के पास रुके और उसका हालचाल पूछा. महिला पहले तो वीआईपी दस्ते की चकाचौंध से थोड़ी परेशान हुई पर उससे तुरंत उबरते हुए उसने जीप में बैठी सोनिया गांधी की ओर इशारा करते हुए पूछा, "एवंगा यारू, ओंगा वित्तुक्करिया?" (वो कौन है, तुम्हारी बीवी या...).

राजनैतिक महत्व और चुनाव से पहले का वक्त चुनने के बावजूद इस यात्रा में भी पुरानी यात्राओं सी समानता थी. लोगों की निजी समस्याएं सुनना, उसके लिए ढीलेढाले अधिकारियों को डांट पिलाना और लोगों से सीधे मिलने का उनका ढंग पुराना ही रहा. इसमें उन्हें मजा आता है. नाडुक्कडु में वे जीप से उतरकर एक महिला, राजलक्ष्मी अम्माल की शिकायत सुनने गए. उसने शिकायत की कि स्थानीय रक्षित मूल्य की दुकान से उसे पाम आयल नहीं मिलता. "दुकानदार मेरे कार्ड पर लिख देता है कि तेल दिया पर तेल मिलता नहीं." मुस्कराते राजीव ने उसे ढाढ़स बंधाया. फिर तुरंत तंजावुर के क्लेक्टर को बुलाकर उस महिला की शिकायत पर ध्यान देने को कहा.

जन संपर्क की दृष्टि से देखें तो यह यात्रा सफल रही. लेकिन वोट बटोरने की कवायद के नाते निश्चित तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. इंका के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, "भीड़ तो जुट रही है पर सवाल यह है कि इसे वोट में कैसे बदला जाए?" राजीव के संदेश का लब्बोलुबाब एकदम स्पष्ट था: राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़िया रहा है और इंका शासन तो और भी बेहतर साबित होगा.

उपस्थित लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए राजीव ने अपने भाषण में हरिजन, वनवासी और पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान पर ही सारा जोर दिया. हरिजनों के लिए बने घरों का उद्घाटन करते हुए हर जगह उन्होंने यह बात कही. हर भाषण में उन्होंने यह बताया कि राष्ट्रपति शासन में हरिजन और वनवासियों से जुड़े मसले देखने के लिए अलग विभाग बनाए गए हैं.

लेकिन भाषण की दूसरी बातें वहां जुटे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाईं. मसलन,

तिरुवरूर में राजीवः मंदिर का सहारा

पीआईबी

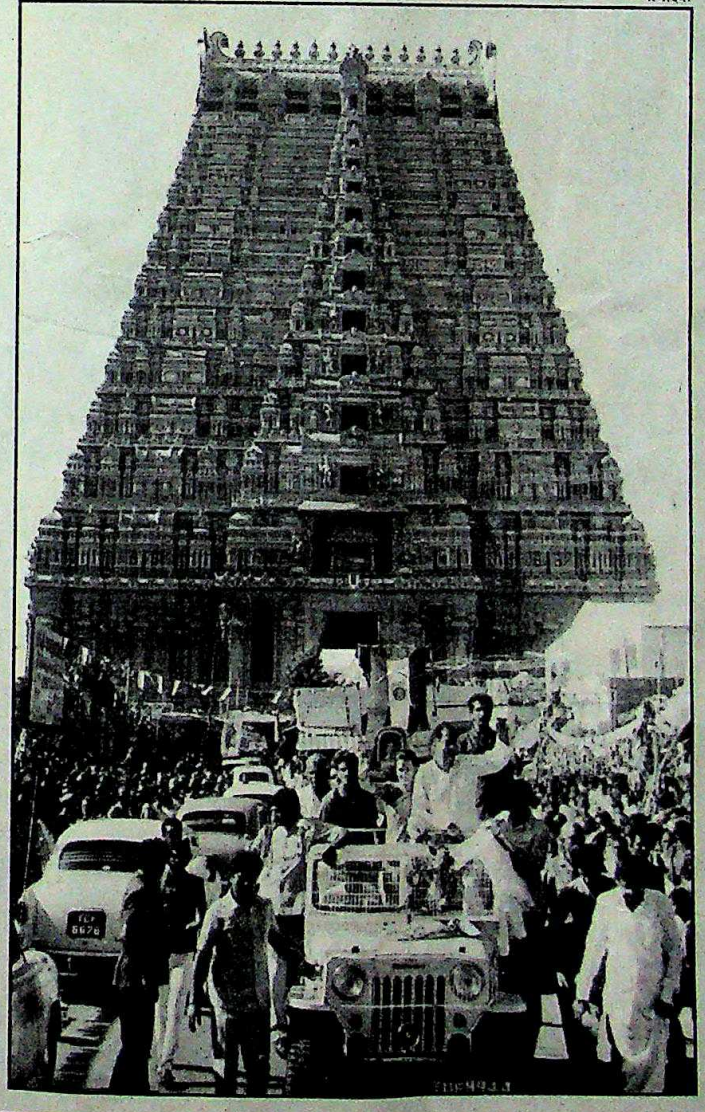

मन्नारगुडी की सभा में उन्होंने कावेरी के पानी के मुद्दे से बात शुरू की. पर इस बारे में कुछ पक्का न कहकर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि केंद्र इलाके की इस प्रमुख समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा.

श्रीलंका मुद्दे पर भी हालांकि उन्होंने केंद्र के रुख का खुलासा किया पर फिर भी लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी. ऐसा इसलिए है कि तंजावुर जिले में बड़ी संख्या में तमिल शरणार्थी और उग्रवादी रहते हैं और इस प्रकार लोग श्रीलंका समस्या से सीधे जुड़ा महसूस करते हैं. प्रदेश इंका के एक नेता ने स्वीकार किया, "श्रीलंका के बारे में इतना लंबा प्रलाप एक गलती थी." और अंत में लाज बचाने जैसे कदम के तौर पर राजीव ने घोषणा की कि दो दिन के अंदर ही इस इलाके के लोगों के फायदे के लिए मेत्तूर जलाशय से पानी छोड़ा जाएगा.

राजीव द्वारा बार-बार दिवंगत कामराज के शासन को तमिलनाडु का स्वर्ण युग बताना भी अनेक कांग्रेसियों को पसंद नहीं आया. प्रदेश इंका के एक महासचिव ने कहा, "कामराज का नाम या नारा अब यहां बहुत दमदार नहीं रह गया है." इसी प्रकार राजीव द्वारा हर सभा में लोगों को तमिल भाषा में नमस्कार करने का भी लोगों ने उतना जोरदार स्वागत नहीं किया. राजीव की दो जनसभाओं में मौजूद रहने वाले नागपत्तनम के एक छात्र जी. स्वामीनाथन कहते हैं, "तमिल बोलने के ऐसे प्रयासों को लोग लोकप्रियता का सस्ता हथकंडा मानते हैं."

दक्षिण आर्कोट जिले के विल्लुपुरम गांव की कृषि मजदूर मरियम्मा ने अधिक समझदारी भरी बात कही, "अब लगने लगा है कि पूरे तमिलनाडु में इंकाई जाग गए हैं. पर अभी उनकी सक्रियता कहीं नहीं दिखाई पड़ती."

—एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शासन की उपलब्धियों का बखान करते हुए राजीव ने घोषणाएं कीं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो जनता 'एक साफ-सुथरे और कुशल प्रशासन के अलावा तेज आर्थिक प्रगति और कमजोर तबकों को विशेष तवज्जो' की उम्मीद कर सकती है.

तमिलनाडु इंका समिति के महासचिव थंगबलु कहते हैं, "प्रधानमंत्री की यात्रा ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया है. दूरदराज के गांवों की यात्रा करके राजीव ने आम जनता के बीच अपनी पहचान बनाई है." लेकिन इन दावों पर बहस हो सकती है.

राजीव की सभाओं में अच्छी-खासी भीड़ जुटी, लेकिन इसे उनकी लोकप्रियता का पैमाना नहीं माना जा सकता. फिर भी इतना तो लगता है कि इंका ने कदम किसी-न-किसी तबके का दिल जीतने का सुनियोजित प्रयास था (देखें बॉक्स).

चुनावी नजरिये से राजीव के ये तूफानी दौरे तर्कसंगत भी हैं. उन्होंने महसूस किया कि राज्य इंका इकाई द्रमुक नेता एम. करुणानिधि और अन्नाद्रमुक के एक धड़े की नेता जयललिता के उग्र चुनावी प्रचारों को जवाब नहीं दे पा रही है. तो उन्होंने उनका जवाब देने का जिम्मा खुद संभाल लिया. हालांकि प्रदेश इंका अध्यक्ष जी.के. मूपनार और उनके सहयोगियों ने द्रमुक के प्रचारों का जवाब देने की भरपूर कोशिश की लेकिन वे राजनीति के चतुर खिलाड़ी करुणानिधि के पासंग भी नहीं ठहरे.

जानकी गुट की राजनैतिक निष्क्रियता को देखते हुए लगता है कि उसने जंग शुरू होने से पहले ही मात खा ली है

हाल तक मुख्यमंत्री पद की सबसे सशक्त दावेदार रहीं जयललिता की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है

राज्य में सेंध लगा ली है. दरअसल, राष्ट्रपति शासन छह महीने बढ़ाने का मकसद साफ है कि इंका को राज्य में अपनी जड़ें जमाने का और समय मिल जाए. और फिलहाल इसकी रणनीति अपने तुरुप के पत्ते—राजीव गांधी—के ही सहारे खेल जीतने की है.

राजीव ने एक-एक दिन में 16-16, 20-20 घंटे विभिन्न जनसभाओं में भाषण दिए और वे छोटे-छोटे कस्बों-गांवों में जा-जाकर लोगों से मिले. उनके दौरे के बाद लोगों को उनकी जीप का गर्दोगुबार ही केवल नहीं मिला, पीने के स्वच्छ पानी और मकान बनाने में आर्थिक मदद के आश्वासन भी मिले. उन्होंने हरिजनों के लिए 8 करोड़ रु. की एक आवास योजना का उद्घाटन भी किया. राज्य के कुल मतदाताओं में 20 फीसदी हरिजन हैं. इसके अलावा उनकी हर सभा, उनका हर बयान और उनका हर

ग्रामीण इलाकों में करुणानिधि की सभाओं में भारी भीड़ जमा हो रही थी और लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुन भी रहे थे. पिछले दो महीनों में करुणानिधि ने तकरीबन 40 दिन तो जनसभाएं करने में ही गुजारे. उन्होंने करीब 200 जनसभाओं को संबोधित किया. और अपनी चुनावी जंग की रसद के तौर पर 2 करोड़ रु. से ज्यादा इकट्ठे भी कर लिए. द्रमुक के स्थायी मुख्यालय के सचिव अर्कोट वीरस्वामी का दावा है, "राष्ट्रपति शासन का भरपूर दुरुपयोग करने के बावजूद इंका राज्य में अपनी जड़ें जमाने में सफल नहीं हुई है."

बहरहाल, अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों की हालत पतली है, यह इंका के लिए वरदान ही है. जानकी के नेतृत्व वाला गुट इस वक्त निष्क्रिय है क्योंकि जानकी डॉक्टरी जांच के लिए अमेरिका गई हुई हैं. लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री की विधवा तो जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएंगी.

दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद की सबसे सशक्त दावेदार जयललिता की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है. यहां तक कि जयललिता के अपने गुट में ही उनके नेतृत्व को खतरा पैदा हो गया है. जाहिर है कि यदि अन्नाद्रमुक के किसी गुट में फिर विभाजन होता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा इंका को ही होगा.

लेकिन इंका अभी यही तय नहीं कर पा रही कि एकला चलो की नीति अख्तियार करे अथवा अन्नाद्रमुक के किसी गुट से चुनावी गठबंधन कर ले. कुछ वक्त पहले तक इंका का एक तबका जयललिता के साथ गठबंधन का हामी था. लेकिन यह बातचीत उसी वक्त खत्म हो गई जब जयललिता ने चुनाव जीतने की स्थिति में इंका को सत्ता में भागीदार बनाने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद से ही इंका ने दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने की नीति अपना ली. लेकिन क्षेत्रीय दलों की जड़ें काटने की उसकी कोशिशें जारी हैं.

इस राज्य की जनता का रुझान हमेशा से व्यक्ति पूजा की ओर रहा है. इसके मद्देनजर इंका ने राजीव की छवि को महिमामंडित करने की मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है ताकि वक्त आने पर वे जनता से कह सकें कि वे राजीव और तमिलनाडु के नेताओं में से चुनाव कर लें. लेकिन इस राज्य के अब तक के चुनावी रिकार्ड को अगर कोई भावी संकेत माना जाए तो यही लगेगा कि राजीव की सारी जद्दोजहद नाकाम भी हो सकती है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

ख़ुश होते . . . मौज मस्ती करते बच्चों को देखना आपको ख़ुश करने के लिए काफ़ी है. बच्चों के लिए जितने ज़रूरी हैं खाना-पीना और हवा उतनी ही ज़रूरी है हंसी-ख़ुशी . . . मौज-मस्ती. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती . . . यही मज़े. एकदम वैसी ही कॉमिक पत्रिका जो हर बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है. आख़िर डिस्नी गैंग के सदस्य दुनिया भर के अरबों बच्चों के चहेते हैं . . . मनपसंद हैं.

बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को ख़ुश कर दीजिए.

यही है अद्‌भुत तरीका बच्चों को यह जताने का कि वे आपकी ज़िंदगी में सदा-सदा सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे. सबसे बढ़िया बात यह कि घर भर में गूंज उठे आपकी चहेती आवाज़.

आपके बच्चे की खिलखिलाहट.

आज ही सबस्क्रिपशन भेजिए और आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें :
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि०
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
वॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न. 69 दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

WM COMICS

डिस्नी टुडे

अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिंदी और अंग्रेज़ी में.

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा
☐ सालानाः रु. 78/- ☐ छह महीने काः रु. 40/- हिन्दी
प्रति के लिए सबस्क्रिपशन. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नं _____ द्वारा कर रहा हूँ.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:

नाम _____

उम्र _____ लिंग _____

डाक-पता _____

_____

_____

विद्यालयः _____

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

114

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

तबादले का 'धंधा' फिर गरम

अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही छह महीने में 30,000 तबादले

राजनैतिक दबावों के चलते या राजनैतिक संरक्षण के लिए नौकरशाहों के तबादले प्रायः हर राज्य में आम हो गए हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में यह एक बेहद 'कमाऊ' धंधा जैसा बन गया है. इससे प्रशासन कितना कुप्रभावित हो रहा है इसकी कोई परवाह ही नहीं की जाती. अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इस धंधे ने जैसे उन्माद का रूप ले लिया है. प्रस्तुत है भोपाल स्थित संवाददाता नरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट:

यह कोई निकम्मी नहीं, काम करने वाली सरकार है. यकीन न हो तो सबूत हाजिर है. 20 जून से 16 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने अपने तकरीबन छह लाख कर्मचारियों में से 30,000 को बोरिया-बिस्तर बांधकर नई जगह पर जाने को मजबूर कर दिया. पिछले छह महीनों में राज्य के हर दूसरे आईएएस और आईपीएस अधिकारी को तबादले के आदेश थमा दिए गए. इनमें से कइयों का तो एक से ज्यादा बार तबादला किया गया.

तीन वर्ष की मंदी के बाद मध्य प्रदेश में तबादलों का 'धंधा' एक बार फिर गरम हो गया है, और 'राजनीति के दलालों' की चांदी फिर कटने लगी है. इस सबका सिलसिला इस साल फरवरी में अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही शुरू हुआ. तबादलों की इस बाढ़ ने तो पिछले महीने राज्य प्रशासन को ही ठप कर दिया. एक और मंत्री थे जो तबादलों की सूची बनाने में व्यस्त थे तो दूसरी ओर अधिकारी इन आदेशों को रद्द करवाने में भिड़े थे. किसी सब-इंजीनियर का तबादला करवाने या उसे रद्द करवाने का 'बाजार भाव' जगह के अनुसार पांच हजार से एक लाख रुपए तक था. विपक्ष के नेता कैलाश जोशी के अनुसार तबादलों का यह उन्माद जब थमा तो 'घूसखोरी, भ्रष्टाचार और राजनैतिक भाई-भतीजावाद की दुर्गंध भर' बाकी रह गई थी.

लेकिन मुख्यमंत्री को इन तबादलों में कोई असामान्य बात नजर नहीं आती. वे कहते हैं, "वर्षों से चली आ रही नीतियों से अलहदा कोई कदम नहीं उठाया गया." लेकिन आंकड़े उनके इस दावे को झुठलाते हैं. सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार पिछले साल भर में जबकि 5,000 अधिकारियों के तबादले किए गए, पिछले एक महीने में मंत्रियों और विभागों के प्रमुखों द्वारा 13,868 तबादलों के आदेश जारी किए गए. तबादलों का जुनून सिंचाई, लोक निर्माण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वन और पुलिस जैसे 'कमाऊ' विभागों पर ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे 'सूखे' विभागों पर भी हावी रहा.

कई मामलों में तो तबादलों के आदेश इतनी तेजी से बदले गए कि हैरत होती है. मिसाल के तौर पर भोपाल के पूर्व कलेक्टर आर.एन. बेरवा को 1 जुलाई को आवास और पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया. अगले ही दिन उन्हें पंजीकरण महानिरीक्षक बना दिया गया और फिर एक महीने के भीतर वापस आवास और पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया. राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास्तव का आरोप है, "तबादले के सभी कायदे-कानून ताक पर रख दिए गए."

तबादलों की यह बाढ़ 20 जून से शुरू हुई. इस दिन अर्जुन सिंह ने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा द्वारा तबादलों पर लगाया गया प्रतिबंध तीन हफ्ते के लिए हटा दिया. इसके बाद लगभग एक महीने तक राजधानी भोपाल में भारी गहमागहमी रही. चिंतातुर अधिकारी जगह-जगह से दौड़े हुए राजधानी पहुंच गए और दबदबा रखने वाले 'बिचौलियों' की तलाश में लग गए. भोपाल के होटलों की भी बन आई. उधर अपने चहेते अफसरों के नाम की पर्चियां लिये विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और छुटभैये राजनीतिकों ने भी राजधानी में डेरा जमा दिया. विधायकों और मंत्रियों के बंगलों के दरवाजों पर दयादृष्टि चाहने वालों की भीड़ लग गई. स्वास्थ्यमंत्री महेश जोशी जैसे मंत्री सुबह से लेकर देर रात तक उन लोगों के आवेदनों को निबटाते रहे जो अपनी मनपसंद जगह तबादले के इच्छुक थे.

ऐसे आवेदनों की संख्या भी अप्रत्याशित ही थी. उच्चतर शिक्षा विभाग के पास 7,500 अध्यापकों के लिए 11,500 आवेदन, नोट और पत्र वगैरह आए, जबकि स्कूली शिक्षा विभाग को अपने 2.25 लाख कर्मचारियों के लिए 4.50 लाख सिफारिशी पत्र मिले. लेकिन आंतरिक सूत्रों का कहना है कि प्रशासन ने 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने की नीति तय कर रखी थी. इसके अनुसार मुख्यमंत्री की सिफारिश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती. इसके बाद क्रमानुसार

कार्टून: अजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंत्रियों, विधायकों, विभागीय सचिवों और विभाग प्रमुखों की सिफारिशों पर गौर किया जाता. अधिकारिक तौर पर ये तबादले 'प्रशासकीय जरूरतों' के मद्देनजर किए गए.

बहरहाल, जैसे-जैसे तबादलों की सूची तैयार होती गई, उन्हें छापने की होड़ भी क्षेत्रीय अखबारों में मच गई. कई बार तो पूरे-पूरे पन्ने में यह सूची छापी गई. और कई बार तो इतना भी हुआ कि तबादलों की अधिकारिक घोषणा से पहले ही सूची लीक हो गई. सिंचाई विभाग की तबादला सूची की साइक्लोस्टाइल कॉपी 50-50 रुपए में बेची गई.

मामला काबू से बाहर होता देख सरकार ने तुरतफुरत आदेश जारी कर दिया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के तबादलों के आदेशों पर 'पुनर्विचार' किया जाए. यानी उसने परोक्ष रूप से यह मान लिया कि तबादलों में गड़बड़ी की गई है. करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का वारा-न्यारा करने वाला सिंचाई विभाग भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सोने की खान से कम नहीं है. वे जानते हैं कि इस विभाग में तबादले के लिए लगाई गई 'पूंजी' जल्दी ही मोटे 'ब्याज' समेत वापस हो जाती है. मुख्यमंत्री भी मानते हैं, "तबादले के इच्छुक सभी लोगों की आंखें सिंचाई विभाग पर ही लगी थीं."

तबादलों के बारे में एक सरकारी निर्देश यह है कि एक समय में एक विभाग के 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकता. लेकिन एक खबर के अनुसार सिंचाई राज्यमंत्री हनुमंत सिंह ने अपने विभाग के 2,800 में से 2,200 अधिकारियों का तबादला कर दिया था. मुख्यमंत्री ने ऐसे 100 अधिकारियों की सूची बनाई है जो जोड़तोड़ में लगे थे. उन्होंने कहा, "मैं जल्दी ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा."

लेकिन ये 100 मामले तो नमूने भर हैं. इस भारी गोलमाल के लिए यदि कोई दोषी है तो वे हैं खुद मुख्यमंत्री. पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा द्वारा तबादलों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा कर इस 'धंधे' को पनपने का मौका उन्होंने ही तो दिया है. हालांकि वोरा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध बहुत प्रभावी नहीं थे, क्योंकि राजनैतिक दबावों के आगे वोरा जल्दी ही घुटने टेक देते थे. फिर भी प्रतिबंधों के चलते तबादलों की संख्या घटकर प्रति वर्ष 5,000 रह गई थी.

मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां तबादलों को हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा वाला 'धंधा' माना जाता है, वहां इतनी भी उपलब्धि महत्वपूर्ण ही मानी जाएगी. इस 'धंधे' के गुर सीखना भी बहुत आसान हैं. धंधे से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी से रकम ऐंठी जा सकती है. रकम इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितने 'मुनाफे वाली' जगह पाना या जाना चाहता है. यह घूस विधायकों के माध्यम से 'ऊपर' तक पहुंचती है. इन नेताओं और उनके चमचों का ज्यादातर वक्त तबादलों की फाइलों का पीछा करने में ही बीतता है. मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह भी मानते हैं कि तबादलों के मामलों के कारण किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता. राजकोष पर भी खर्च बढ़ जाता है. मिसाल के तौर पर इस साल हुए तबादलों के कारण सरकार को कर्मचारियों के भत्तों के मद में 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे.

इसके अलावा पूरी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैलता है और कर्मचारियों के मनोबल पर जो बुरा असर पड़ता है उसका अंदाज लगा पाना संभव नहीं है. कर्मचारियों का तबादला अक्सर बरसात के मध्य में भी (जैसा कि इस बार भी हुआ है) कर दिया जाता है जब बच्चों के स्कूल का सत्र बीच में ही होता है. इससे उन्हें बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने में मुश्किलें आती हैं. मध्य प्रदेश सरकार के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एन.पी. शर्मा कहते हैं, "ऐसे बरताव के बाद भी क्या वे कर्मचारियों से कार्यकुशलता की अपेक्षा कर सकते हैं?" कर्मचारी संघ ने तबादला नीति के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस पर राज्यव्यापी धरना आयोजित करने का फैसला किया है. एक खाद्य निरीक्षक का मामला उनके पक्ष को मजबूत ही करेगा. उसका छह साल में ही 40 से भी अधिक बार तबादला किया गया. अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद ही यह क्रम रुका.

और इस साल तो बार-बार तबादलों के चलते कुछ हास्यास्पद स्थितियां भी पैदा हो गईं. रायगढ़ जिले में सरकार ने एक ऐसे

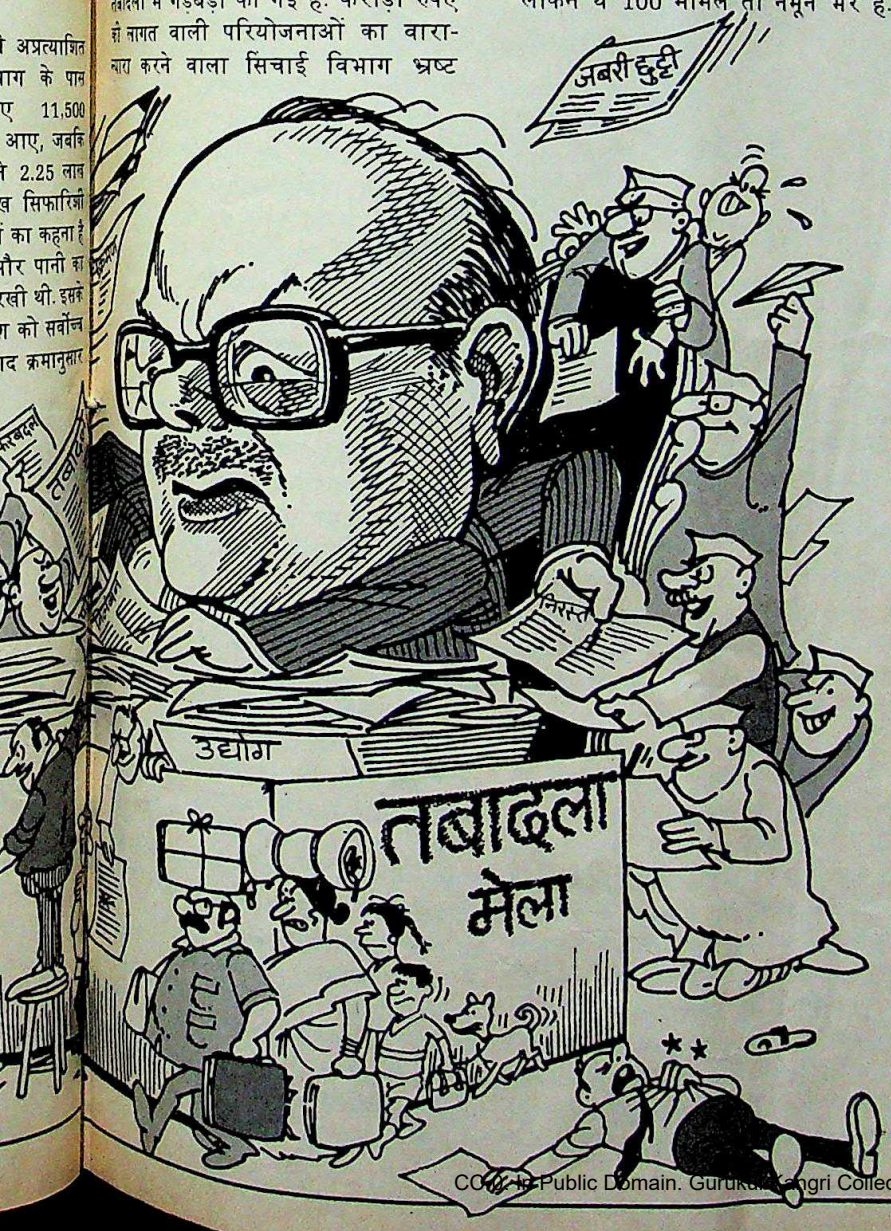

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वनरक्षक का तबादला कर दिया जिसकी पिछले साल मौत हो गई थी. इसी जिले में स्कूली शिक्षा विभाग में ऐसे दो लोगों का तबादला कर दिया गया जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे. राजस्व विभाग ने तो एक नई मिसाल ही कायम कर दी. उसने कई पटवारियों को तबादले के आदेश थमा दिए जिसमें यह नहीं लिखा था कि तबादला कहां किया गया है. कई कर्मचारियों के तबादले तो ऐसी जगहों पर किए गए जहां रिक्ति थी ही नहीं.

मनमाने तबादलों के कारण दफ्तरों, स्कूलों और अस्पतालों में कर्मचारियों की संख्या और स्वरूप में ऊटपटांग फेरबदल भी हो जाते हैं. बड़े शहरों के अस्पतालों और स्कूलों में तो कर्मचारियों की भरमार हो जाती है जबकि दूरदराज के इलाकों के स्कूलों और अस्पतालों में कर्मचारियों का अकाल पड़ जाता है. इसका एक कारण तो यह है कि हरेक कर्मचारी हमेशा इसी जुगाड़ में रहता है कि कैसे वह अपने जिले या शहर या गांव में पदस्थापित हो जाए. ऐसा नहीं हो पाता तो वे शहरों में ही पदस्थापन की कोशिश करते हैं.

1956 में कई इलाकों का विलय करके मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था. लेकिन लोगों में क्षेत्रीय भावनाएं अभी भी प्रबल हैं. समस्या को विकट बनाने वाला तथ्य यह है कि सरकारी नौकरियों में ग्वालियर और रीवा क्षेत्र के अधिक लोग हैं. ये लोग जब अपने-अपने इलाकों में ही तबादले की कोशिश करते हैं तो जाहिर है कि फैसला रिश्वत की रकम पर होता है.

लेकिन सबसे अधिक भ्रष्टाचार फैलाती है राजनीति. नेता लोग गांव के पटवारी तक को राजनैतिक नजरिये से देखते हैं. इसलिए जब सरकार बदलती है तो बड़े अधिकारियों के साथ-साथ छोटे बाबुओं और शिक्षकों तक का तबादला हो जाता है. तीन वर्षों के जनता शासन में 1.39 लाख कर्मचारियों का तबादला हुआ था. संयुक्त विधायक दल (संविद) सरकार (1967-69) के जमाने में भी स्थिति कोई बेहतर नहीं थी.

आर.सी. साहू

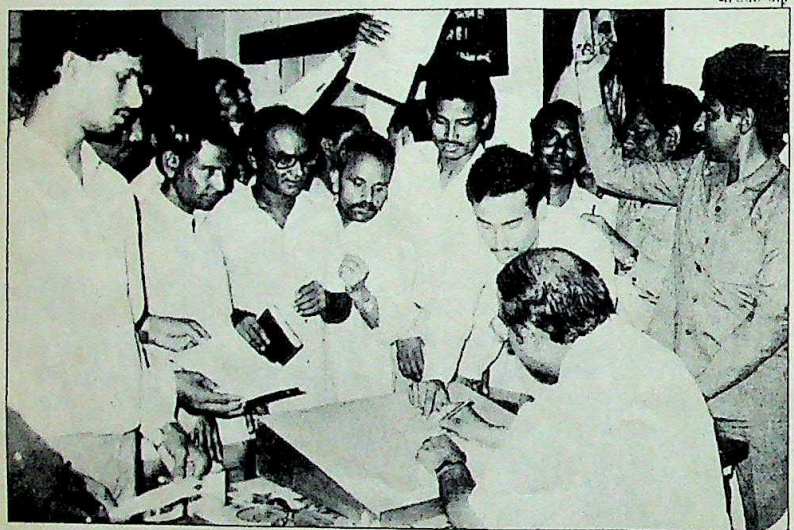

स्वास्थ्यमंत्री महेश जोशी की तरह राज्य के कई मंत्री सुबह से देर रात तक उन लोगों के आवेदनों को निबटाते रहे जो अपनी मनपसंद जगह तबादले के इच्छुक थे

लेकिन तबादलों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में माहिर तो अर्जुन सिंह ही हैं. 1980 में जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो उनका कोई बड़ा राजनैतिक आधार नहीं था. यह आधार बनाने के लिए, समर्थकों को जीतने और विरोधियों को सजा देने के लिए उन्होंने इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया. तबादला करने की 'पावर' के मामले में मुख्यमंत्री के बाद मंत्रियों का नंबर आता है. जिस साल अर्जुन सिंह ने सत्ता संभाली उस साल तो उन्होंने सांसदों और विधायकों के लिए भी अनधिकृत तबादला कोटा तय कर दिया. हर किसी को प्रत्येक विभाग में पांच तबादले कराने की 'पावर' दे दी गई इसका परिणाम यह हुआ कि 55,000 तबादले हुए और इनसे जुड़े कई घोटालों से विधानसभा गूंज उठी.

इस भ्रष्ट प्रक्रिया में पार्टी विधायकों के शामिल होने की बात स्वीकार करने की 'हिम्मत' भी अर्जुन सिंह ने दिखा दी. लेकिन इसकी उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की— 'प्रशासनिक काम में नौकरशाही और विधायिका के बीच न्यायिक संतुलन रखना.' बाद में उन्होंने इस मुद्दे को और साफ किया कि नौकरशाही को उद्दंड और जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील होने से बचाने के लिए विधायकों को इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं.

जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक परिपत्र भेज कर मुख्यमंत्रियों से कहा कि तबादलों के मामलों में राजनैतिक दबाव न पड़ने दिया जाए और ये 'यथासंभव' प्रशासनिक स्तर पर ही हों तो अर्जुन सिंह ने अपना रवैया एकदम बदल दिया. 1982 में मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि तबादले के लिए या उन्हें रद्द कराने के लिए या फिर प्रोन्नति और पदस्थापन के लिए पैरवी करना कानूनन अपराध होगा और इस जुर्म में छह महीने तक की सजा हो सकती है. बाद में यह अध्यादेश 'मध्य प्रदेश विशेष भ्रष्टाचार निवारक कानून, 1983' में बदल गया. अर्जुन सिंह ने विधायकों और सांसदों को चिट्ठी लिखकर इस अध्यादेश के बारे में बताया और उन्हें 'सलाह' दी कि वे तबादले आदि के लिए पैरवी न करें.

इसका कुछ असर भी पड़ा. 1983 में सिर्फ 15000 कर्मचारियों के तबादले ही हुए. राज्य सरकार ने तबादलों में होने वाली हेराफेरी पर नजर रखने के लिए एक अदद कमेटी भी नियुक्त की. तबादले का आदेश न मानने और उसे रद्द कराने की कोशिश करने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने की धमकी भी दी गई.

पांच साल बाद अर्जुन सिंह की हालत फिर वही ढाक के तीन पात वाली है. वे सांसदों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को 'संतुष्ट' करने में लगे हैं. सारे मंत्री भी इसी मुहिम में लग गए हैं. वे भी विधायकों की सिफारिशें टालकर संकट मोल लेना नहीं चाहते. प्रसिद्ध प्रशासक एम.एन. बुच कहते हैं, "इस व्यवस्था की कमजोरियों से ही कालाबाजारियों, अपराधियों, भ्रष्ट अधिकारियों, अकुशल नौकरशाहों, शोषकों और लुटेरों को पोषण मिलता है." लेकिन यहां तो व्यवस्था के भीतर कमजोरी जानबूझ कर बनाई गई है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंदिरा हत्याकांड

अहम मुकदमा

सबकी निगाहों का केंद्र

यह हत्या का कोई साधारण मुकदमा नहीं था. इस लंबे मुकदमे का हर कदम इतिहास का एक अंग था और पिछले 44 महीनों से पूरा देश दम साधे इस पेचीदा कानूनी नाटक के पटाक्षेप के इंतजार में था. इंदिरा गांधी हत्याकांड का मुकदमा जहां तीन अभियुक्तों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था, वहीं इसके राजनैतिक, अंतरराष्ट्रीय और कानूनी पहलुओं को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई थी.

शुरू में बचाव पक्ष का वकील बनने को कोई तैयार नहीं था लेकिन बाद में कुछ तेजतर्रार वकीलों ने इस मुकदमे को हाथ में ले लिया. जहां के.एल. अरोड़ा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया, वहीं बचाव का जिम्मा पी.एन. लेखी और आर.एस. सोढी ने संभाला. बचाव पक्ष के इन दोनों वकीलों की देशभक्ति पर कुछ उन्मादी हलकों की ओर से उंगलियां भी उठाई गईं. मामला ऊपरी अदालतों में पहुंचा तो मैदान में वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी और अतिरिक्त महान्यायवादी जी. रामास्वामी सरीखे भी आ गए.

यह लंबी कानूनी लड़ाई थी. 247 दिनों तक चली 110 सुनवाइयों के दौरान अभियोग पक्ष ने 73 गवाह प्रस्तुत किए. बचाव पक्ष तीन गवाह ही पेश कर पाया.

मुकदमा कोई कम सनसनीखेज नहीं रहा. शुरू में ही सतवंत ने यह कहकर धमाका कर दिया कि बेअंत की श्रीमती गांधी के शक्तिशाली निजी सहायक आर.के. धवन से 'अच्छी दोस्ती थी.' जेठमलानी ने इस मुद्दे को लपक लिया. उन्होंने संकेत दिया कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति धवन को फंसाने की कोशिश कर रहा है. बाद में उन्होंने यह मांग कर डाली कि इस हत्याकांड और उसके बाद हुए दंगों के बारे में ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए (सरकार ने इसे दबा दिया है). वे न्यायमूर्ति एम.पी. ठक्कर को भी गवाही के लिए बुलाना चाहते थे.

लेकिन मुकदमे की असल सुनवाई के दौरान तो पूरा नाटक एक छोटे-से कमरे में सिमट आया था. सबसे ज्यादा सुरक्षा इंतजामात वाले इस मुकदमे के लिए तिहाड़ जेल के नजदीक ही विशेष रूप से एक अदालती कक्ष तैयार किया गया था.

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से बलबीर सिंह की सजा को उलट दिया. उन पर बेअंत सिंह के साथ षड्यंत्र में शामिल रहने का आरोप था. बलबीर को दूसरे हत्यारे सतवंत सिंह और षड्यंत्र में शामिल केहर सिंह के साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह की सजा बेअंत की पत्नी की गवाही के आधार पर बरकरार रखी जिसमें उसने कहा था कि इस अपराध के कुछ दिनों पहले वे दोनों अमृतसर से नदारद हो गए थे और घर पर भी आपस में कुछ कानाफूसी करते रहते थे. बेअंत के चाचा केहर ने उसे अमृत छकने के लिए भी प्रोत्साहित किया था.

प्रशांत पंजियार

बलबीर तिहाड़ जेल से रिहा होने पर; सतवंत (ऊपर) और केहर (बाएं)

बलबीर की बेअंत के साथ बस जान-पहचान भर थी. वह भी इसलिए कि वे दोनों प्रधानमंत्री निवास में तैनात थे. सितंबर में दोनों ने प्रधानमंत्री निवास के बाहर एक पक्षी देखा जिसे उन्होंने 'गुरु दा बाज' (गुरु गोविंद सिंह का बाज) करार दिया. अभियोग पक्ष की दलील थी कि उन्होंने इसे स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करने का बदला लेने का संकेत माना.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बलबीर की इस दलील को माना कि उसे हत्याकांड के दूसरे दिन पकड़ा गया और 33 दिन तक गैर-कानूनी हिरासत में रखने के बाद षड्यंत्र में फंसा दिया गया. अभियोग पक्ष की यह कहानी कि उसे एक बस स्टॉप से पकड़ा गया था, अदालती जिरह के आगे टिक नहीं पाई. दूसरा अहम साक्ष्य भी धराशायी हो गया जिसके मुताबिक उसकी जेब से ऐसे कागजात जब्त किए जिन पर कुछ अस्पष्ट तारीखें, नाम और 'जी चाहता है हत्या कर दूं' सरीखे वाक्य लिखे पाए गए. अदालत ने कहा कि कोई पुलिस अफसर अपराध के एक महीने बाद ऐसे कागजात लेकर घूमेगा, इससे "पुलिस की समझदारी के बारे में तो छोड़िए उसके तौर-तरीकों की समझ का भी अभाव" जाहिर होता है. बलबीर का कहना था, "अगर मुकदमे की सुनवाई सार्वजनिक रूप से हुई होती तो न्यायाधीशों को मुझे दोषी साबित करने में परेशानी पेश आती." बरी होने के बाद उनकी पहली टिप्पणी थी, "इस देश में इंसाफ अभी जिंदा है."

अब केहर और सतवंत सुप्रीम कोर्ट से मामले पर पुनर्विचार करने की अपील करेंगे. अगर उसमें भी सजा बहाल रही तो उन्हें फांसी के फंदे से राष्ट्रपति की माफी ही बचा सकती है. सरकार ने भी हालांकि बलबीर को बरी किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील करने की सोची है पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना स्पष्ट है कि उन पर कोई आंच नहीं आती दिखती. उनके घर पर भी खुशी का माहौल था. चार बच्चों में उनकी सबसे छोटी बेटी पांच वर्षीया मिन्नी इस बात से बेहद खुश थी कि पापा उस खौफनाक घर को छोड़कर 'उसके घर' वापस आ गए हैं. —डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अफगानिस्तान

भावी मुसीबतों के संकेत

अमन की ओर बढ़ते-बढ़ते अंदरूनी जंग के आसार तेज

रूसी सेना 1979 की सर्दियों में जब सीमा पार कर अफगानिस्तान में घुसी थी उस साल कड़ाके की ठंड पड़ी थी. बर्फ ने हिंदूकुश के ऊंचे-ऊंचे दर्रों को जमा दिया था. पूरा काबुल जैसे ठिठुर गया था. नौ साल बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई है तो इस साल रिकार्डतोड़ गरमी पड़ रही है. तापमान कई बार 40 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है और काबुल पसीने से तरबतर है.

अफगानियों के लिए ऐसा मौसम अपशकुन हुआ करता है. उनका मानना है कि यह आने वाली मुसीबतों का संकेत है. लोककथाओं के मुताबिक अपने बच्चों को चेतावनी देने का अल्लाह का रंग ही निराला है.

ये दंतकथाएं जुलाई महीने पर एकदम खरी उतरीं. रूसी सेनाओं की वापसी के आसार से मुजाहिदीनों और अफगानिस्तान सरकार के बीच जब जंग खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे, ऐन उसी वक्त काबुल गुरिल्ला हमलों की चपेट में आ गया है. चीन और मिस्र में बने 122 एमएम रॉकेटों से लैस मुजाहिदीनों ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया है.

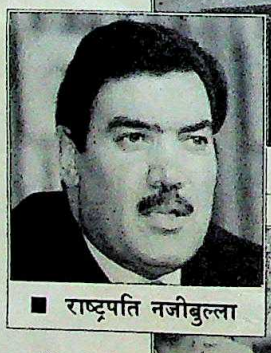

■ राष्ट्रपति नजीबुल्ला

काबुल स्थित पश्चिमी राजनयिकों का मानना है कि 16 से 23 जुलाई के बीच शहर में कम-से-कम 200 रॉकेट फटे होंगे. इससे पहले के तीन हफ्तों में अंदाजन ऐसी 123 वारदातों के मुकाबले इस गोलाबारी ने शहर की फिजां को और गरमा दिया है. अगस्त में ऐसी वारदातों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन हमले अभी जारी हैं.

नतीजतन काबुल का भविष्य अधर में लटक गया है. रूसी सेनाओं और बख्तरबंद दस्तों ने शहर के चारों ओर फिर मोर्चा जमा लिया है. राजनयिकों का मानना है कि रूसी सेनाओं ने शेवाकी की कारागा झील और शहर के पश्चिम में अफगानी सेना की जगह ले ली है. उनका दावा है कि रूसी वायुसेना का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, खासकर जलालाबाद, गजनी और गारदेज सरीखे शहरों पर उसका दबाव है जहां से हाल ही में सेनाएं हटाई गई थीं.

फ्रांसीसी दूतावास और जर्मन क्लब पर रॉकेट हमलों के अलावा अमेरिकियों के बाल-बाल बचने के बाद ज्यादातर राजनयिक मिशनों ने अपने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया है. ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इस महीने के मध्य तक वापस चले जाएंगे. अमेरिकी और पाकिस्तानी दूतावासों में ज्यादातर लोग अविवाहित हैं इसलिए इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी दूतावासों ने यही फैसला किया है. भारतीय दूतावास के लोग कहते हैं कि वे शायद अपने आश्रितों को 'स्वेच्छा' के आधार पर लगभग अगले महीने तक घर भेज दें. दो दशकों से चल रहे भारतीय स्कूल को भी दिसंबर में बंद करने पर विचार चल रहा है.

संयुक्त राष्ट्रसंघ भी कठिन परिस्थितियों में फंसा है. इसके प्रतिनिधि चूंकि अभी सद्भावना मिशन में शामिल हुए हैं, इस वजह से वह कूटनीतिकों द्वारा देश छोड़कर

■ शांति झंडे उठाए अफगान सैनिक: तनावपूर्ण शांति

■ कार की तलाशी: बारूद के ढेर पर बैठा शहर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाने की योजना की हिमायत नहीं कर सकता. इसलिए उसने अपने विदेशी कर्मचारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. वे रात 10 बजे बाद के कर्फ्यू में भी काम करते हैं. थोड़े अच्छे होटल इंटरकांटिनेंटल में उनका जाना भी इसलिए वर्जित कर दिया गया है कि वह मुजाहिदीनों का संभावित निशाना है.

असल बात यह है कि अप्रैल में हुआ जेनेवा समझौता शांति स्थापित नहीं कर पाया है. यह करार कारगर साबित होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब कई चरणों में मिलेगा. पहला मौका तो 15 अगस्त को ही आएगा जब तक रूसी सेना के अपने 50 फीसदी सैनिक लौटा लेने का कार्यक्रम है. आखिर यह 50 फीसदी क्या बला है?

रूसी सेनाध्यक्ष मार्शल सर्जेई अखरोमेयेव के मुताबिक मई में सेना की वापसी की शुरुआत के वक्त अफगानिस्तान में 1,15,000 सैनिक मौजूद थे. इसका मतलब है कि अगस्त के मध्य तक कम-से-कम 57,000 सैनिकों की वापसी होनी चाहिए. लेकिन अफगानिस्तान में रूसी टुकड़ियों की वास्तविक कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बोरिस ग्रोमोव महज 1,03,000 सैनिकों की मौजूदगी स्वीकार करते हैं. इसका मतलब है कि इस महीने करीब 51,500 सैनिकों की वापसी होगी. लौट गए रूसी सैनिकों की संख्या पर भी अखरोमेयेव और ग्रोमोव के आंकड़े एक नहीं हैं.

लेकिन 15 अगस्त के बाद रूस सेनाएं निकालना जारी रखेगा, कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं. दरअसल अगर रूस की नजर में जेनेवा समझौते का कथित उल्लंघन होता रहा तो माना जाता है कि वह शायद वहां जमे रहने, वापसी स्थगित करने या उसका कार्यक्रम फिर से तैयार करने का विकल्प चुनेगा.

और फिर, 15 अगस्त के बाद रूसी सैनिकों की वापसी का मामला अभी स्पष्ट नहीं है. जेनेवा समझौते में 15 फरवरी 1989 तक पूरी सेना की वापसी के अलावा क्रेमलिन के लिए और कोई लक्ष्मण रेखा नहीं तय की गई है. लेकिन इसमें अभी छह महीने हैं. अहम मुद्दा यह है कि क्या बाकी 50 फीसदी सेना की वापसी धीरे-धीरे होगी अथवा वे वापसी की तारीखें तुरत-फुरत घोषित करने के बाद लौट जाएंगी? इससे मुजाहिदीन अटकलबाजी में फंस गए हैं. सबसे अहम बात है कि वापसी अगर सर्दियां शुरू होने के बाद हुई तो बर्फ बागियों और उन्हें मिलने वाली मदद के आड़े आ जाएगी.

लेकिन एक और अहम सवाल अभी अनुत्तरित है कि रूसी सेनाओं के लौट जाने के बाद क्या होगा? निश्चित रूप से कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुजाहिदीन हॉलीवुड स्टाइल में झंडे उठाकर और ढोल-ताशे बजाते हुए विजय जुलूस लेकर काबुल वापस आ जाएंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं.

वियतकांग की तरह मुजाहिदीन भी परंपरागत लड़ाई लड़ने में न तो सक्षम हैं और न उन्हें वैसा प्रशिक्षण हासिल है. उनके पास टैंक, भारी हथियार और वायुसेना का अभाव है. न ही उनके साथ उत्तर वियतनाम सरीखा कोई मददगार है. हालांकि मुजाहिदीन रॉकेट

मुहम्मद हसन शर्क़

'पाकिस्तान वादाखिलाफी कर रहा है'

मुहम्मद हसन शर्क़ को अभी हाल ही में अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है. वे नजीबुल्ला सरकार के सबसे महत्वपूर्ण प्रवक्ता के रूप में बहुत जल्दी उभरे हैं. भारत में राजदूत रह चुके शर्क़ अपने देश में अमन के रास्ते में आने वाली नई रुकावटों के बारे में अधिकारपूर्वक बोलते हैं. करण थापर के साथ उनकी बातचीत के अंश:

• *काबुल में रॉकेटों से किए जा रहे हमलों पर:*

ये हमले सबूत हैं कि पाकिस्तान जेनेवा समझौते को तोड़ रहा है.

• *पाकिस्तान के रवैये पर:*

पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल अफगानिस्तान को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है. पाकिस्तान हमारी मुखालफत करने वालों को हथियार, गोला-बारूद और प्रशिक्षण दे रहा है.

• *राजनयिकों के आश्रितों को निकालने की योजना पर:*

यह फैसला पाकिस्तान से हमारे खिलाफ हो रहे प्रचार के असर में किया गया है. काबुल में रह रहे राजनयिकों को हर तरह की सहूलियतें मुहैया कराई गई हैं. लेकिन यह फैसला तो उन्हें ही करना है कि वे अपने परिवार को रखना चाहते हैं या वापस भेजना चाहते हैं.

• *क्या रूस 15 अगस्त तक अपने 50 फीसदी फौजियों को हटा लेने का अपना वचन पूरा करेगा:*

मुझे रूस के इस वायदे पर यकीन है. मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि अफगानिस्तान और रूस जेनेवा समझौते के तहत अपने वायदों को पूरा करेंगे.

• *यदि पाकिस्तान जेनेवा समझौते को तोड़ता रहा तो क्या रूस 15 फरवरी '89 तक अपने सभी फौजियों को हटाने का अपना कार्यक्रम पूरा करेगा या इसमें फेरबदल करेगा?*

कोई पक्ष अकेला किसी समझौते को नहीं मान सकता. आप ही सोचिए कि हमें रूसी फौजियों को अपने देश में क्यों बुलाना पड़ा. महज इसलिए कि दूसरे देशों ने हम पर हमला कर दिया था. जाहिर है, हमला बंद होने पर रूसी फौजी वापस जाएंगे.

• *मुजाहिदीन कमांडरों से समझौता वार्ताओं पर:*

यह बदकिस्मती ही है कि बाहरी दखलंदाजियों के कारण हमारी बात ठीक से सुनी नहीं जाती. लेकिन हमें मालूम हुआ है कि मुखालिफ पार्टियां भी मानने लगी हैं कि जंग जारी रहने से फायदा नहीं. यह सरकार अपना फलसफा दूसरों पर थोपने या गद्दी पर बने रहने के लिए नहीं लड़ेगी. समझौते के लिए यह हमारी शुरुआती पेशकश मानी जा सकती है.

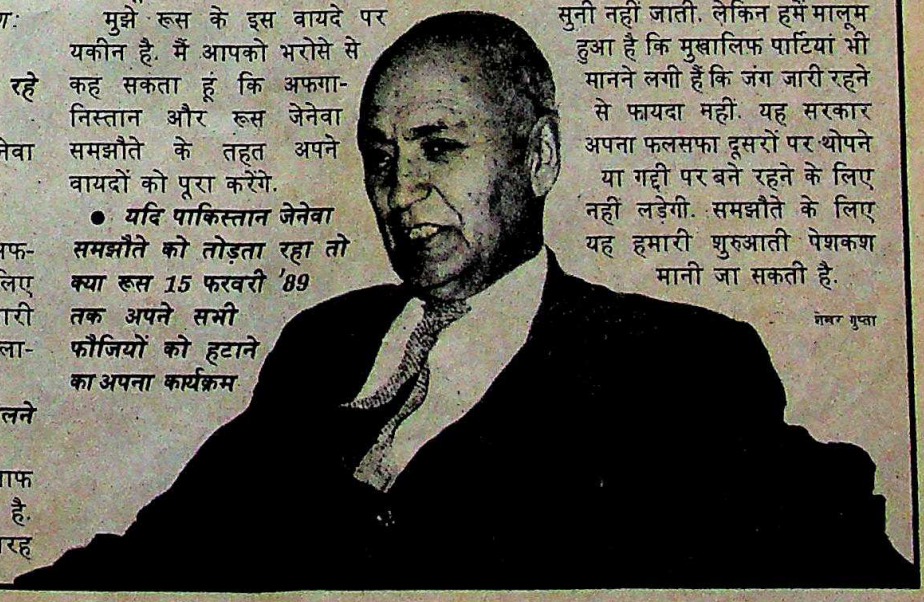

नवीन गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमले करने में सक्षम हैं लेकिन रूसी इलेक्ट्रॉनिक सुसज्जित हथियारों की जवाबी कार्रवाई के आगे उन्हें बचाव का रास्ता ढूंढ़ते रहना पड़ता है. इस वजह से बागियों के निशाने सही नहीं लगते और वे क्षुब्ध होकर ऐसी कोई कार्रवाई कर बैठते हैं जिसका नतीजा होता है कि उनके संभावित समर्थक आतंकित होकर उनसे कट जाते हैं. और यदि वे रॉकेट ज्यादा खुलकर दागें तो उन्हें वायुसेना का निशाना बनने का खतरा रहता है.

लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि रूसी सेनाओं की वापसी के बाद नजीबुल्ला सरकार टिकी ही रहेगी. मुजाहिदीनों का गुरिल्ला युद्ध तनावग्रस्त और उद्विग्न जनता का हौसला पस्त कर सकता है. काबुल के तमाम जिलों में उनके सहभागी मौजूद हैं ही. 1929 में कबायलियों ने अव्यवस्थित मगर विध्वंसकारी विद्रोह करके बादशाह अमानुल्ला को गद्दी से उतार फेंका था. और 1989 में शहरी बगावत नजीबुल्ला की जड़ें खोद सकती हैं. ज्यों-ज्यों दबाव बढ़ेगा नरमपंथियों द्वारा आतंरिक विद्रोह कर तख्ता पलटने की संभावना भी बढ़ती जाएगी. इसके बाद सरकार ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह सकती है. और अगर रूस युद्धबंदियों के बारे में सीधे मुजाहिदीनों से बातचीत करने के अपने फैसले पर इसी महीने अमल करता है तो संकट जल्दी भी आ सकता है और वह भी दूसरी तरफ से.

यही वजह है कि अब सारा दारोमदार राष्ट्रपति नजीबुल्ला को मिलने वाले समर्थन पर टिका है. उनका खास जोर मुजाहिदीनों के प्रमुख कमांडरों— पंजशीर घाटी के अहमद शाह मसूद, हेरात के इस्माइल खां और काबुल क्षेत्र के अब्दुल हक को फुसलाने पर है. पिछले कई हफ्तों से सौदेबाजी चल रही है और सरकार ने क्षेत्रीय स्वायत्तता से लेकर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने तक का प्रस्ताव रखा है. इसमें रक्षा मंत्रालय, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सरीखे पद भी शामिल हैं. पर अभी तक इन्हें स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है. मसूद ने अपने नियंत्रित इलाके से रूसी सेनाओं की वापसी के दौरान हालांकि कोई हमला नहीं किया. हालांकि सरकार नियंत्रित 'काबुल टाइम्स' ने लिखा है कि 'काबुल के जिलों से सशस्त्र बागियों' द्वारा जुलाई में ईद-उज-जुहा की छुट्टियों के दौरान राजधानी में अपने रिश्तेदारों से मिलने आने के लिए क्षमादान कबूल कर लिया है. बावजूद इसके कोई समझौता होना सपना ही लगता है.

फिलहाल दोनों पक्ष एक-दूसरे को तौल रहे हैं. शायद शक्ति परीक्षा से ही सरकार को जरूरी समझौता करने की जरूरत महसूस हो और मुजाहिदीन इस नतीजे पर पहुंचें कि वे एकतरफा जीत हासिल नहीं कर सकते. लेकिन दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान में ऐसी चरम सीमा पर पहुंचकर भी शायद कोई सम्मानपूर्ण समझौता संभव नहीं है. बल्कि इससे केवल हत्याओं, अलगाव, लूटपाट और अराजकता को ही बढ़ावा मिलेगा. इतिहास गवाह है कि जब भी अफगानिस्तान में ऐसे हालात पैदा हुए हैं तो खूनखराबे का ही दौर शुरू हुआ. काबुल की लंबी गर्मियों की शुरुआत शायद अभी हुई है.

—करण थापर, काबुल में

जिया-उल-हक

बात का बतंगड़

लगता है जनरल जिया की पिछले महीने की यह आश्चर्यजनक घोषणा कि 10,000 रूसी सैनिक अफगानिस्तान लौट आए हैं, गलतफहमी पर आधारित थी और इससे पहले उन्होंने तथ्यों की जांच-परख नहीं की थी. कुछ ही दिनों के भीतर उनके विदेशमंत्री ने यह बयान वापस ले लिया.

'काबुल स्थित राजनयिकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सद्भावना मिशन के प्रमुख जनरल हेलमनन के साइप्रसवासी राजनैतिक सलाहकार बेनन सावेन को रूसी चेतावनी का गलत अनुवाद दिया गया था. रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान जेनेवा समझौते का कथित उल्लंघन करता रहेगा और खास तौर पर मुजाहिदीनों को सैनिक साजसामान और प्रशिक्षण देता रहेगा तो वह फिर से संतुलन कायम करने के लिए 10,000 सैनिक अफगानिस्तान भेज सकता है. माना जाता है कि इस संदेश में यह भी जोड़ा गया था कि जरूरत पड़ने पर रूस चार दिनों के भीतर 10,000 सैनिक भेज सकता है.

लेकिन लगता है कि सावेन को इस चेतावनी का जो अनुवाद मिला उसका मतलब यह निकला होगा कि रूस महज धमकी नहीं बल्कि 10,000 सैनिकों को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है.

लेकिन जनरल जिया की घोषणा में सारी बातें तोड़-मरोड़कर रखी गई थीं. इससे पश्चिमी देशों की राजधानियां रूसी 'धोखेबाजी' के प्रति एकदम सतर्क हो उठीं. लगा कि अमेरिका में रूस विरोधियों की स्थिति मजबूत हो गई है. पर रूसियों ने जिया के दावे का खंडन किया. उधर, अफगान विदेश मंत्रालय ने भी इसे निराधार बताया.

काबुल स्थित पश्चिमी राजनयिकों का शुरू से ही मानना था कि जनरल जिया गलत कह रहे हैं. इनमें से एक ने बेझिझक कहा, "मैं जानता था कि यह निरी बकवास है." एक दूसरे राजनयिक की टिप्पणी, थी "ऐसी अनर्गल बात का जन्म कैसे हुआ, यह जानकर मुझे हंसी ही आई." एक तीसरे की टिप्पणी थी, "इससे यही पता चलता है कि एकदम गलत खबरें किस तरह पहुंचती हैं."

लेकिन जनरल जिया के उतावलेपन का एक फायदा तो हुआ ही. वह यह कि पश्चिमी देशों ने इसके प्रति जो प्रतिक्रिया दिखाई उसके मद्देनजर रूस आइंदा ऐसी धमकी देने के बारे में सोचेगा भी नहीं.

—करण थापर

■ राष्ट्रपति जिया-उल-हक: भारी गलती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचतन्त्र

पढ़ने की मौज रंगन की मस्ती

Near the river
That curves and bends,
Lived these four
Remarkable friends.

The deer, one day,
Fell in a hunter's trap.
She was found missing
When they woke from their nap.

मोड़दार वलखाती
इक नदी के पास,
रहते थे चारों
ये अनूठे यार।

एक दिन हिरनी
फंसी जाल में शिकारी के,
पता कहीं न पाया उसका
नींद से जब जागे वे।

बच्चों, तुम्हारें मनोरंजन के लिए आधुनिक चित्रों से सुसज्जित कुछ पुरानी रोचक भारतीय कहानियाँ. यह कहानियाँ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखीं हैं. ताकि तुम दोनों भाषाओं का आनन्द उठा सको. रेखाचित्र विशेष रुप से बनाये गये हैं जिसमें तुम स्वयं मनपसंद रंग भर कर एक रंगीन पुस्तक तैयार कर सकते हो.

इस श्रंखला की चारों पुस्तकें वी.पी.पी. से केवल रु. 20/- में लेने के लिए अपने नाम व पते के साथ निम्नलिखित पते पर लिखिए : लिविंग मीडिया प्रा. लि., डायरेक्ट मेल युनिट, थौमसन प्रेस बिल्डिंग, देहली-मथुरा रोड़, फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा).

यह पुस्तकों की श्रंखला लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. के नाम चैक, मनी आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट भेजने पर भी मिल सकती है.

अभी कोई पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान

सिखों को सिर्फ सरकारी शह

लोग तरजीह नहीं देते

एक ओर तो पाकिस्तान पर पंजाब में सिख आतंकवादियों को शह देने का आरोप लगाया जाता है, दूसरी ओर हकीकत यह भी है कि सिखों के कुछ सबसे पवित्र मंदिर पाकिस्तान में ही हैं. सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहब लाहौर में है, तो पंजा साहब इस्लामाबाद के पास. सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जहां निधन हुआ था वह डेरा साहब भी लाहौर में ही है. भारत और दूसरे देशों के हजारों सिख साल में कई बार जत्था बनाकर इन मंदिरों की यात्रा करते हैं. पाकिस्तान में बसे सिख कैसा अनुभव करते हैं, इस बारे में विशेष संवाददाता ***रमिंदर सिंह*** *ने वहां के सिखों से बात की और यह भी पता लगाया कि खालिस्तान के प्रति उनमें कितना समर्थन है. उनकी रिपोर्ट:*

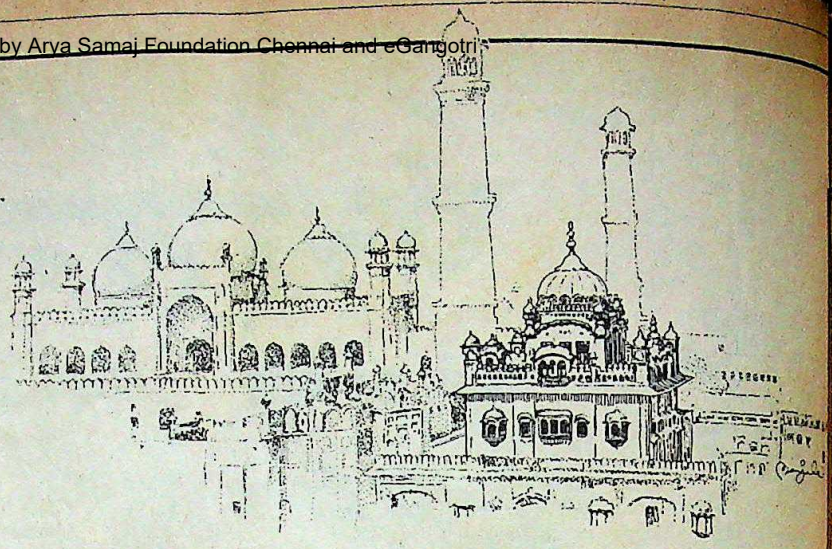

लाहौर में रणजीत सिंह की समाधि उपेक्षित पड़ी है. पाकिस्तानी भी इस बात से खुश नहीं हैं कि लाहौर को 'खालिस्तान' की राजधानी बताया जाता है

बंटवारे के पहले के दिनों की याद करके सैयद चन्न शाह की आंखें कहीं अतीत में खो जाती हैं. उनके पूर्वजों के नाम पर बसे रावलपिंडी के मोहल्ले शाह चन्न चिराग में जब मैं अपने पुश्तैनी घर की खोज में घूम रहा था तो उनसे मुलाकात हो गई. वे मजार की देखभाल करते हैं. उनके स्कूल मास्टर साथी गुलाम सबीर भी पुराने दिनों की याद में खो जाते हैं. पुश्तैनी घर की खोज बेकार साबित हुई क्योंकि मुहल्ले का पूरा हुलिया ही बदल गया है. गलियां बदल गई हैं, और लोग भी बदल गए हैं. मेरे पिता के बचपन के साथी सब गुजर चुके हैं. लेकिन जैसे ही मेरे आने की खबर लोगों को लगी, वे घरों से बाहर आए और मुझसे मेरे पुश्तैनी घर का हुलिया सुनकर वहां तक पहुंचने का रास्ता बताने लगे. यह सब कुछ अतीत के लिए मोह और एक तरह का अपराध बोध भी जगा रहा था. रावलपिंडी में कभी बड़े-बड़े सिख जमींदार हुआ करते थे. आज जिन इमारतों में प्रेसीडेंसी है वे कभी सरदार बहादुर मोहन सिंह की थीं. मोहल्ला शाह चन्न चिराग भी सिखबहुल था. और इस मोहल्ले में भी इस संप्रदाय के प्रति अपराध बोध का ही भाव है.

"हिंदुस्तान से कोई लड़ाई लड़ना पाकिस्तान के लिए खामख्याली ही होगी"

फख्र इमाम
भंग नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष

अतीत के प्रति मोह और यह अपराध बोध—इन दोनों तत्वों से आज इन दो देशों और इसके लोगों के रिश्ते बहुत हद तक प्रभावित हैं. लेकिन जहां तक सिखों की बात है, अतीत के प्रति यह मोह भी एक तरह की उग्रता लिये हुए है. इसके कारणों की तलाश करना भी बहुत मुश्किल नहीं है. बीते हुए दिनों की याद करने वाला हर शख्स बंटवारे के दिनों की याद भी करता ही है और यह भी कि सिख और मुसलमान किस तरह एक-दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे. सिखों के बारे में पाकिस्तानियों की धारणा बंटवारे के समय हुए दंगों में उनकी भूमिका और फिर भारत के साथ हुए तीन युद्धों में उनकी बहादुरी के किस्सों से जरूर प्रभावित है. और जले पर नमक छिड़कने वाली बात 1971 में हुई जब पूर्वी पाकिस्तान में 90 हजार सैनिकों को एक सिख जनरल के सामने हथियार डालना पड़ा. वर्षों से भारत विरोधी प्रचारों से प्रभावित पाकिस्तानियों के लिए सिख चेहरा जैसे भारत का सबसे सटीक प्रतीक बन गया है. लाहौर की गलियों में आज कोई भी सिख गुजरे, लोग उसे बिना घूरे नहीं छोड़ते.

इसका एहसास उन्हीं सिखों को हो सकता है जो कभी पाकिस्तान घूम आए हों. सबूत की जरूरत हो तो पंजाब में होने वाली हत्याओं पर वहां के समाचार माध्यमों में दी गई रिपोर्टों को लिया जा सकता है. पाकिस्तान टेलीविजन पर समाचार पढ़ने वाले अक्सर कहते हैं कि पिछले 24 घंटों में 'पूर्वी पंजाब' के सिखों ने इतने लोगों की हत्या कर दी. सरकार नियंत्रित अखबार 'पाकिस्तान टाइम्स' भी हत्याओं के लिए दोष अक्सर सिखों पर ही मढ़ता है. उन्हें आतंकवादी कहने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान के दो प्रमुख उर्दू अखबारों ने जब यह खबर छापी कि भारत नजीब सरकार की मदद के लिए अपनी शांति सेना काबुल भेज रहा है तो कहा गया कि इसमें सिख लाइट इन्फैंट्री के जवान ही होंगे.

लेकिन पाकिस्तान के शहरी अभिजात्य वर्ग के लोगों में ऐसा पूर्वाग्रह या विद्वेष नहीं दिखता. वे बड़े आदर और नम्रता से पेश आते हैं. पाकिस्तान का अक्सर दौरा करने वाले वरिष्ठ पंजाबी और सिख पत्रकार ज्यादातर इन्हीं लोगों से मिलते-जुलते हैं और बीते हुए दिनों की साझा यादों को ताजा करते हैं. लेकिन यह उनकी मान्यताओं को प्रभावित करता है.

तो सिखों के प्रति आम पाकिस्तानियों का रवैया कितना सहानुभूतिपूर्ण है? कतई बहुत सहानुभूतिपूर्ण नहीं. सीमा पार कथित खालिस्तान के लिए चल रहे संघर्ष के बारे में उनका एहसास? कह सकते हैं कि गरदन में हुए दर्द जैसा. 'मुस्लिम' के पूर्व संपादक मुसाहिद हुसैन कहते हैं, "पंजाबी मुसलमानों की पुरानी पीढ़ी के लोगों का रवैया सिखों के प्रति नकारात्मक ही है. उन्हें लगता है कि बंटवारे के दिनों में मुसलमानों के सबसे खिलाफ सिख ही थे. वे मानते हैं कि सिखों ने ही तब ऐसे हालात बना दिए थे कि पंजाब में लोग घर छोड़कर सरहद पार भागने को मजबूर हो गए थे." कुछ और पाकिस्तानी हस्तियां और पाकिस्तान में रह चुके कुछ राजदूत भी हुसैन की इस मान्यता का समर्थन करते हैं. अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम सफदर बट्ट कहते हैं, "मैं समझता हूं कि सिखों के लिए पाकिस्तान में कोई हमदर्दी नहीं है. मैं तो यह मानता हूं कि वे दोनों तरफ फायदे में हैं. उनकी शिकायतें बहुत वाजिब नहीं हैं." बट्ट पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख रह चुके हैं और जिया के करीबी माने जाते

सभी रेखाचित्र: मंजुला पद्मनाभन

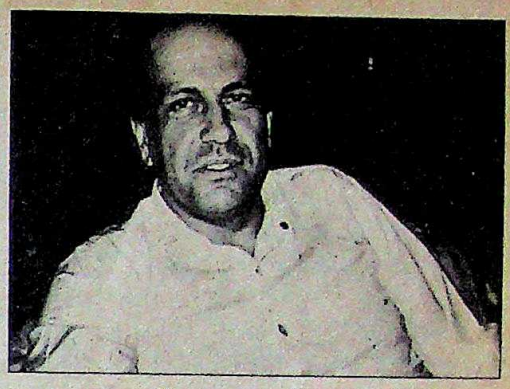

"हम सरहदी इलाकों में रैलियां करते रहे हैं और हमें पता है कि 1984 में हजारों सिख पाकिस्तान चले आए थे"

सलमान तासीर
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रवक्ता

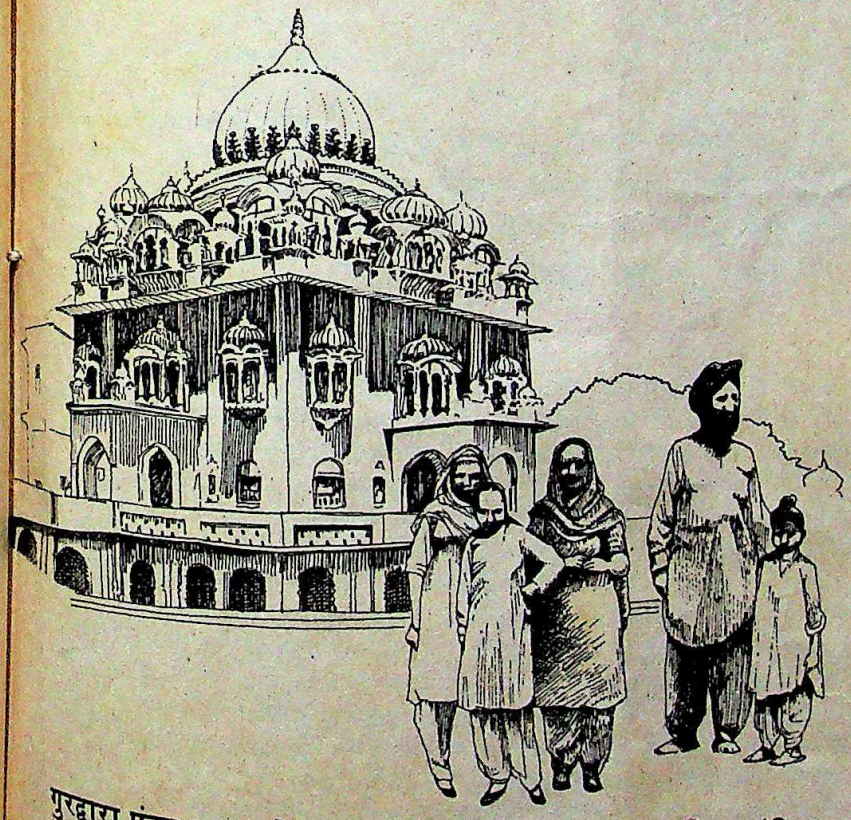

गुरद्वारा पंजा साहब के अलावा सिखों के कुछ सबसे पवित्र मंदिर पाकिस्तान में ही हैं. भारत और दूसरे देशों के हजारों सिख जत्था बनाकर साल में कई बार इन मंदिरों की यात्रा करते हैं

हैं. उन्हें पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का फायदा ही दिखता है, "मुझे लगता है कि पंजाब में बांग्लादेश वाली हालात हो गई है. 1971 में जिस तरह बंगालियों का दिल टूट चुका था, उसी तरह आज सिख भी अलग-थलग महसूस कर रहे हैं." उन्हें इस बात का संतोष है कि उन्हें लेने के देने पड़ रहे हैं. वे कहते हैं, "जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे."

सिख आतंकवादियों को लाहौर या इस्लामाबाद की गलियों में घूमते हुए नहीं पाया जा सकता. ठीक वैसे ही जैसे किसी ने आतंकवादियों को एके-47 बंदूकें देते हुए नहीं देखा हो. इसका मतलब यह नहीं है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण नहीं मिलती या मदद नहीं मिलती या जो लोग खरीदना चाहें उन्हें एके-47 उपलब्ध नहीं. पाकिस्तानी पत्रकार बताते हैं कि एके-47 तो घंटे के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता है और अक्सर शादियों में हवाई गोलियां दागने के लिए उन्हें किराए पर लिया भी जाता है. पंजाब के आतंकवादियों के पास इन हथियारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है और वे आसानी से उन्हें हासिल कर लेते हैं. अफगान मुजाहिदीन आंदोलन का गढ़ पेशावर हथियारों से पटा हुआ है और पंजाब के आतंकवादियों के लिए अच्छा बाजार है.

बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लाहौर स्थित प्रवक्ता सलमान तासीर कहते हैं, "इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) अफगान मुजाहिदीनों के लिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुकर्रर करोड़ों डॉलर मूल्य के हथियारों की हेरफेर करता रहा है जिसके कारण यह पूरा इलाका बारूद का ढेर बन गया है. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार सिर्फ इसलिए इन हथियारों पर कोई रोक लगाएगी कि इनसे भारत को परेशानी हो रही हैं.'' वे आगे कहते हैं, ''हम सरहदी इलाकों में रैलियां करते रहे हैं और हमें पता है कि 1984 में हजारों सिख सरहद पार करके पाकिस्तान में चले आए थे. पहले वे कुछ कैंपों में रहे और फिर वापस चले गए.''

आज यही सबसे बड़ा सवाल है. क्या आज भी ऐसे शिविर चल रहे हैं? पाकिस्तान जिस तरह पंजाब में अपनी दखलंदाजियों के आरोपों का खंडन करता है उसी तरह इन शिविरों के बारे में भी खंडन करता है. लेकिन कुछ सबूत हैं जिन्हें परिस्थितिजन्य कहा जा सकता है. मैंने पंजाब के दो सिखों को (जिनमें से एक केसरिया पगड़ी पहने हुए युवक था) पेशावर के यूनिवर्सिटी टाउन गेस्ट हाउस के बाहर घूमते हुए देखा. अफगान मुजाहिदीनों के सात दलीय मोर्चे के नेता गुलबादीन हिकमतियार और कुछ दूसरे नेता भी यहां अक्सर आते हैं. भंग नेशनल असेंबली की एक प्रमुख सदस्या आबिदा हुसैन इंग्लैंड में सिख परिवार के पड़ोस में बसे अपने रिश्तेदारों का किस्सा बताती हैं—उनके सिख पड़ोसियों ने उनसे पंजाब सीमा के पास के गांव में बसे उनके रिश्तेदारों के पते मांगे. आबिदा ने बताया, ''मुझे बाद में यह पता चला कि पंजाब से कुछ सिख उनके रिश्तेदारों के यहां कुछ हफ्ते आकर रहे थे.''

सबूत जितना महत्वपूर्ण होता है, मंशा उससे कम महत्वपूर्ण नहीं होती. पंजाब में गड़बड़ी होती रहे यह पाकिस्तान की मंशा हो सकती है. इसे समझने के लिए वहां आज सेना की हैसियत को समझना होगा. पाकिस्तानी सेना 1971 में बांग्लादेश में हुई पराजय की शर्म भूल नहीं पाई है. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकांश विपक्षी नेता और नागरिक यह मानने लगे हैं कि पाकिस्तानी सेना आलसी होती जा रही है. जनरल जिया भी यही कोशिश करते रहे कि ज्यादा-से-ज्यादा सैनिक दस्तों को सऊदी अरब या खाड़ी के देशों में भेजा जाए जहां भारी तनख्वाह मिलती है. इस सबका नतीजा यह है कि आज सेना के अधिकारी पाकिस्तान के नवधनाढ्य वर्ग में प्रमुख हैं. सलमान तासीर कहते हैं, ''लोगों को डर हैं कि सेना अब अपनी सरहदों की रखवाली करने के काबिल नहीं रह गई है.'' पूर्व अध्यक्ष और भंग नेशनल असेंबली के 18 सदस्यीय संसदीय विपक्षी गुट के नेता फ़ख्र इमाम कहते हैं, ''भारत से भिड़ना पाकिस्तान के लिए खामख्याली ही होगी.''

यह एहसास ऐसे समय हुआ हैं जब भारत अपने को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिशों में लगा है. पंजाब में अस्थिरता बनी रहे और वहां की आबादी अलग-थलग महसूस करती रहे यह पाकिस्तान के लिए रणनीतिक तौर पर फायदेमंद ही होगा. पाकिस्तान के प्रमुख पुस्तक प्रकाशक नज़म सेठी कहते हैं कि इसी कारण पाकिस्तानी अधिकारी आतंकवादियों की आवाजाही की ओर से आंख मूंदे रहते हैं, बल्कि यहां तक कि वे उन्हें उन ठिकानों का पता देते हैं जहां से आधुनिक हथियार चोरी-छिपे खरीद कर लाए जा सकते हैं.

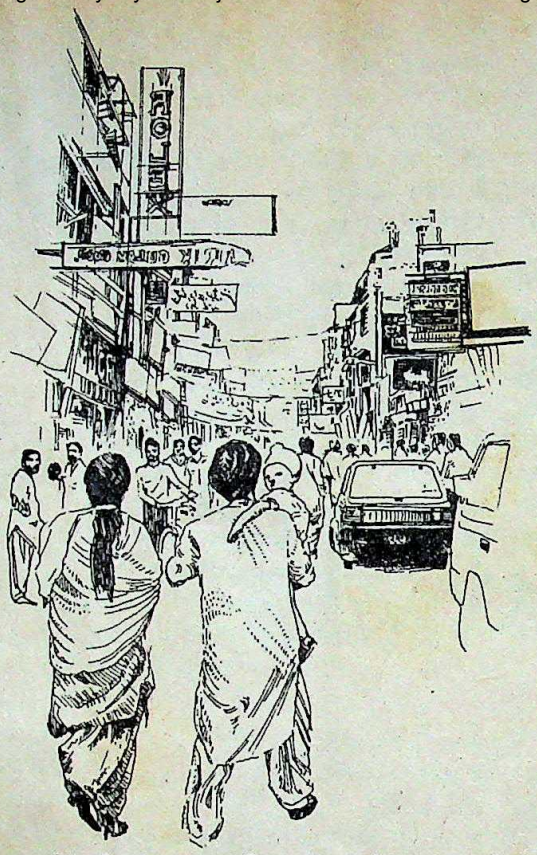

लाहौर के अनारकली बाजार में आज कोई भी भारतीय गुजरे तो लोग ध्यान नहीं देते मगर कोई सिख गुजरे तो लोग उसे बिना घूरे नहीं छोड़ते

अधिकांश पाकिस्तानी यही मानते हैं कि उनकी सरकार पंजाब के मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं कर रही है. ऐसा शायद इसलिए है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर गाहे बगाहे बढ़-चढ़कर ऐसे आरोप लगाती रही है और पाकिस्तान उन्हें खारिज करता रहा है. अब हालत यह है कि किसी भी सिख को देखकर पाकिस्तानी उस पर संदेह करने लगते हैं. अधिकांश पाकिस्तानी अब लाहौर को महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी के रूप में याद नहीं करना चाहते. बल्कि वे अपनी जड़ों की तलाश में फारस और अफगानिस्तान की ओर रुख करने लगे हैं. लाहौर के विशाल शाही फोर्ट में रणजीत सिंह की समाधि आज उपेक्षित पड़ी है. और अब तो खालिस्तानी संगठनों ने एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसमें लाहौर को कथित खालिस्तान की राजधानी बताया गया है. जाहिर है कि पाकिस्तानियों को यह सब कतई पसंद नहीं होगा.

भारत के लिए और सिखों के लिए दुख की बात तो यह है कि पंथक कमेटी और दूसरे खालिस्तानी संगठन यह नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें भारत को परेशान करने के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. आज पंथक कमेटी भारत सरकार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान को दोस्त भले समझ ले लेकिन अगर कभी सरकार के साथ मुठभेड़ में सिख बड़ी तादाद में मारे जाते हैं तो पाकिस्तान में शायद ही कोई आंसू बहाने वाला होगा. और खतरा यह भी है कि मोहरे जब अपनी चमक खो देते हैं तो उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है. दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त ही नहीं होता.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गति अवरोधक रास्ते में आए

मोटर कंपनी स्टैंडर्ड मोटर्स के कामकाज के मामले में उद्योगपति ए.सी. मुथैया और कंपनी के प्रबंध निदेशक कार्तिक नारायण के रिश्ते अब उतने अच्छे नहीं रहे. नारायण के परिवार ने ही यह कंपनी शुरू की थी. मुथैया भारी-भरकम रासायनिक खाद और रसायन कंपनी सदर्न पेट्रोकेमिकल्स के प्रबंध निदेशक हैं. उनकी निवेश कंपनियों ने कुछ महीने पहले नारायण के परिवार से स्टैंडर्ड मोटर्स के 44 फीसदी शेयर खरीद लिए थे. अब इस परिवार के पास 29 फीसदी शेयर ही रह गए हैं. सीबीआई के छापे के बाद कंपनी मुश्किल में पड़ गई. मुथैया ने इसे संकट से उबारने के लिए पैसा लगाया. तय हुआ था कि वे कंपनी के रोज-रोज के कामकाज में दखल नहीं देंगे. लेकिन सदर्न पेट्रोकेमिकल्स वालों को इस कंपनी में प्रमुख पदों पर बिठाने से नाराजगी पनपने लगी. अभी विभाजन तो नहीं हुआ है. लेकिन ऐसा होने का मतलब होगा कंपनी से किसी एक की विदाई.

जान डालने की कोशिश

सीमेंट उद्योग की दिग्गज एसीसी ने अगले पांच वर्षों में अपने कारखानों को आधुनिक बनाने, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने और नई मशीनें लगाने पर 900 करोड़ रु. लगाने की योजना बनाई है. औद्योगिक विकास बैंक (दूसरे वित्तीय संस्थानों के साथ एसीसी में जिसके 40 फीसदी शेयर हैं) को दिए प्रस्ताव में कंपनी ने 10 करोड़ रु. तक में दक्षिण भारत में एक छोटी सीमेंट रिफ्रेक्टरी खरीदने की बात भी कही है. अभी तक इसके पास सिर्फ एक ही रिफ्रेक्टरी है, इसलिए यह प्रस्ताव आकर्षक है. इतनी बड़ी योजनाओं के लिए पैसा खुद एसीसी, वित्तीय संस्थाओं और विश्व बैंक से आएगा. यह कोशिश इस बुढ़ाती जा रही कंपनी में नई जान डालने के लिए है. पिछले साल तो कंपनी को थोड़ा मुनाफा हुआ भी था वरना कई वर्षों से यह अपने पुराने पड़ गए कारखानों के कारण घाटे में चल रही थी. इसी कारण कामकाज सुधारने की कोशिश कर रहे थे. इसी अभियान के तहत कंपनी के तीन कारखाने बेच दिए गए और चौथे को बंद कर दिया गया. साथ ही 4500 कर्मचारियों की विदाई भी कर दी गई.

दिल टूटे, बात बिगड़ी

भारतीय दवा निर्माता संघ के पदाधिकारियों के बीच मनमुटाव के बुरे नतीजे सामने आने लगे हैं. दिल्ली की दवा कंपनी रैनबैक्सी ने इस संघ से रिश्ता तोड़ लिया है और उम्मीद है कि कुछ और भी कंपनियां संघ से नाता तोड़ेंगी. संघ में दवा उद्योग की कैडिला लेबोरेटरीज और युनिकेम जैसी 'देसी' कंपनियां इसकी सदस्य हैं. इसके अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों में आजकल छत्तीस का रिश्ता हो गया है. अगर और सदस्य कंपनियों ने भी नाता तोड़ लिया तो यह संघ सिर्फ छोटी कंपनियों का प्रतिनिधि रह जाएगा.

नाम में ही सब कुछ

डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज जल्दी ही अपना नाम डालमिया इंडस्ट्रीज करने जा रही है. 1970-71 से ही यह कंपनी डेयरी के धंधे में थी लेकिन हाल में इसने जायदाद, सोडा ऐश और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी हाथ लगाया है. संजय डालमिया का यह 30 करोड़ रु. का नया उद्यम दरअसल दूरसंचार और लीजिंग का है. और इसी विस्तृत कारोबार की पहचान कराने के लिए नाम में बदलाव किया जा रहा है.

छुपे रुस्तम

तीसरी दुनिया की 100 प्रमुख कंपनियों की सूची में 18 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है. इनमें से 10 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं. इनमें इंडियन आयल कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और राज्य व्यापार निगम (देखें चार्ट) शामिल हैं. 'साउथ' नामक पत्रिका द्वारा तैयार इस सूची में निजी क्षेत्र के ये नाम हैं: टाटा समूह, बिड़ला समूह, मोदी समूह, टिस्को, आरपीजी एंटरप्राइजेस, टेल्को और जेके समूह. लेकिन इनमें से कोई भी प्रथम 10 में शामिल नहीं हैं. 49 देशों की कंपनियां सूची में हैं जिनमें करीब आधे नाम ब्राजील, भारत और दक्षिण कोरिया की कंपनियों के हैं. तीसरी दुनिया के 10 प्रमुख बैंकों की सूची अलग है जिसमें सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक का नाम है. और इसका स्थान भी आठवां है.

चार्ट: बी.के. शर्मा

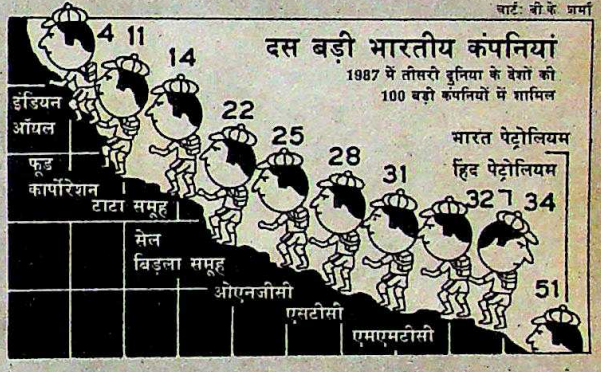

फैशन बेचेंगे

कई बड़ी कंपनियां सिलेसिलाए कपड़ों के धंधे में पैर पसारने लगी हैं. विजयपत सिंघानिया की कंपनी रेमंड वूलन मिल्स पुरुषों के तैयार कपड़े बेचने की शुरुआत कर ही चुकी है. जो दूसरी कंपनियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं उनमें एस.के. बिड़ला की बीएक्सएल इंडिया, धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और बाटा कंपनी शामिल है. बीएक्सएल देसी और विदेशी बाजार के लिए वूलन सूट, रिलायंस पुरुषों-महिलाओं के लिए फैशन वाले कपड़े और बाटा भी कीमती पोशाक बनाना चाहती है. वितरण का नेटवर्क और खुद कपड़ा तैयार करने की क्षमता तो है ही उनके पास. रिलायंस जैसी कंपनी के पास अच्छा नाम (विमल) भी है जिसका फायदा लिया जा सकता है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिलायंस

सितारा फिर दमकने लगा

सरकार की कई नीतियां भी अंबानी के हक में रहीं

लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं. धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मद्धिम पड़ता सितारा फिर दमकने लगा है. बंबई के इसके मुख्यालय में छाया उत्साह का माहौल स्पष्ट संकेत देता है कि बुरे दिन लद चुके हैं.

कई महीनों की मंदी के बाद कंपनी के दोनों मुख्य उत्पादों—पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर और पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की बिक्री फिर बढ़ गई है. कंपनी के लीनियर अल्काइल बेंजीन (लैब) और प्यूरीफाइड टेरीफ्थेलिक (पीटीए) संयंत्र शुरू होने के वक्त उठी समस्याएं अब सुलझा ली गई हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल कंपनी के रिकार्ड मुनाफा कमाने की उम्मीद है.

चर्चा है कि सिंथेटिक कपड़े बनाने वाली यह धुरंधर कंपनी कुछ और बड़ी योजना (गुजरात गैस क्रैकर कांप्लेक्स) हासिल करने, कुछ कंपनियां हथियाने और महत्वाकांक्षी निर्यात अभियान छेड़ने जा रही है.

ये लक्षण इसलिए भी अहम हैं क्योंकि 1986 में अंबानी की किस्मत खराब चल रही थी. सरकारी नीतियों के चलते माहौल उतना अनुकूल नहीं था. नतीजतन 1985 के 71.34 करोड़ रु. के मुकाबले 1986 का लाभ 14.17 करोड़ रु. आ गया. लाभांश भी 50 से घटकर 25 प्रतिशत हो गया.

अंबानी भी ग्रहदशा सुधरने का फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं. इस पखवाड़े रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स 516 करोड़ रु. इकट्ठा करने के लिए शेयर बाजार में उतर रही है. इससे गुजरात के हजीरा में लग रहे 700 करोड़ रु. के पेट्रोरसायन उपक्रम के लिए रकम जुट सकेगी.

ज्यादातर व्यापारी उतार-चढ़ाव वाले शेयर बाजार में कदम रखने से परहेज करते हैं लेकिन अंबानी पर कोई असर नहीं. रिलायंस ने तो अपने परिवर्तनीय ऋणपत्रों की गारंटी के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों और बैंकों से गुजारिश तक नहीं की है. कंपनी का यह आत्मविश्वास यों ही नहीं है. ऋणपत्र जारी होने के दो हफ्ते पहले ही देश भर में अनधिकृत तौर से एक ऋणपत्र पर 80 रु. के प्रीमियम की दर चल रही है.

अंबानी का जादू फीका नहीं पड़ा है. कंपनी ने बंबई में जो सम्मेलन किया उसमें 1000 से अधिक दलाल शामिल हुए. आम तौर पर ऐसे सम्मेलनों में 100 से अधिक दलाल नहीं आते. ताजा उत्साह को देखते हुए शेयर बाजार के जानकार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस निर्गम की कई गुना अधिक बुकिंग होगी. बंबई के एक दलाल ने कहा, "बुकिंग ज्यादा होगी, तब भी मुश्किल ही है."

ऐसे जबरदस्त उत्साह के बावजूद रिलायंस अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

सरकार के विवादास्पद फैसलों की वजह से रिलायंस को रिकार्डतोड़ फायदा होने की चर्चा चल पड़ी है....

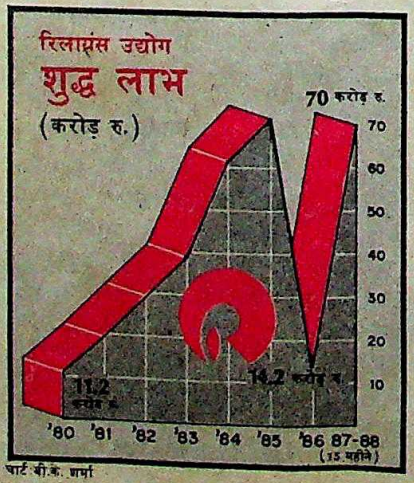

चार्ट बी.के. शर्मा

टीवी पर प्रभावी विज्ञापन आने लगे हैं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपा वह विज्ञापन तो सर्वत्र चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें ऐसे किसी परिवार की कन्या मांगी गई है जिसने रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में निवेश किया हो.

ऐसी शोशेबाजी बेवजह भी नहीं. कुछ निवेश विश्लेषकों को भरोसा है कि यह बड़ा भारी निर्गम शेयर बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा. बंबई की अरिधि इन्वेस्टमेंट्स के विश्लेषक फिरोज रंगूनवाला कहते हैं, "इस निर्गम पर बहुत कुछ निर्भर है. इसकी सफलता-असफलता से पूरे शेयर बाजार के भविष्य पर असर पड़ेगा."

ऐसा हो सकता है. लेकिन इस निर्गम की कामयाबी यह भी बताएगी कि लोग रिलायंस के हाल के कामकाज को किस तरह आंकते हैं. कंपनी के कामकाज का अंतिम ब्यौरा तो निर्गम के बाद ही आएगा लेकिन इसे लेकर बहुत चिंता नहीं है. 1986 में बिक्री 904 करोड़ रु. थी जो इस साल (15 महीने में) 1,323 करोड़ रु. हो गई है. उम्मीद है कि मुनाफा 100 करोड़ रु. तक (18 महीने में) पहुंच जाएगा. 30 फीसदी अंतरिम लाभांश

नामस भोजानी

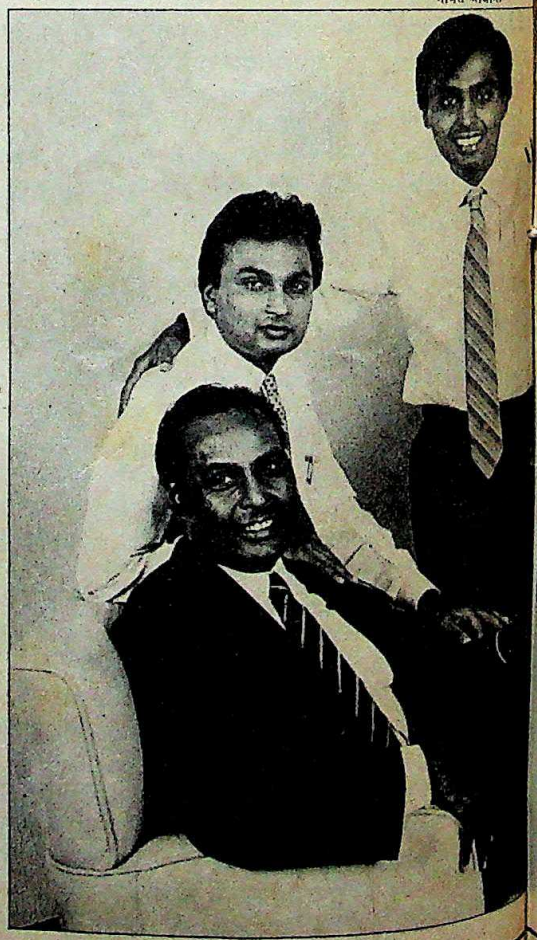

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तो पहले ही दिया जा चुका है.

इस हंगामे में एक बात भुला दी गई कि रिलायंस ने अपना वित्त वर्ष दो बार आगे बढ़ाया है. वित्त वर्ष बढ़ाने के पीछे मंशा चाहे बुरी न हो पर इतना तय है कि इससे कंपनी को फायदा हुआ. सरकार ने बजट में उत्पाद-कर में भारी छूट दी. अब इसका असर कंपनी के स्थिति-विवरण में देखने को मिलेगा.

लेकिन इस सबसे रिलायंस के आलोचकों को कोई आश्चर्य नहीं होगा. एक के बाद एक घोषणाओं से सरकार ने सिंथेटिक कपड़ा उद्योग को काफी मदद पहुंचाई और इनसे रिलायंस बव्वर शेर बन गया है. सही हो या गलत पर कई लोगों का मानना है कि सरकारी घोषणाएं रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए ही की गईं.

बजट में की गई घोषणाओं के कारण पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर और पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादकर में काफी कमी हो गई. सिंथेटिक कपड़ा उद्योग के एक जानकार के अनुसार, "स्पष्ट रूप से रिलायंस को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि इन दोनों चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक वही है."

बजट के बाद सरकारी फैसलों से भी रिलायंस को फायदा हुआ. पिछले साल सरकार ने पोलिएस्टर धागे के लिए जरूरी कच्चे माल पीटीए पर कर में प्रति टन 3,000 रु. की कमी कर दी. कुछ महीने बाद

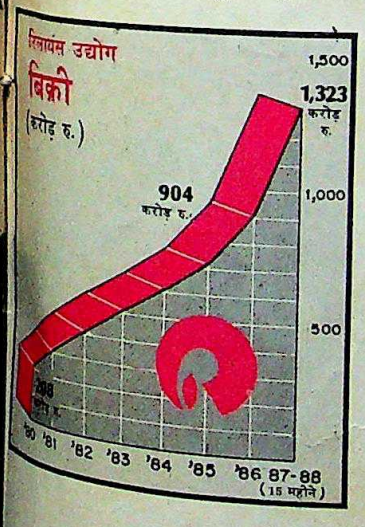

...और बिक्री में भी बढ़ोतरी हो गई है. हालांकि वर्ष के ज्यादातर अरसे में कंपनी का सितारा मद्धिम ही रहा

"हम रिलायंस की मदद नहीं कर रहे. जब भी यह कंपनी शामिल होती है, नीतिगत फैसले सावधानी से किए जाते हैं"

एच.के. खां
पेट्रोकेमिकल्स सचिव

प्रभात पटियार

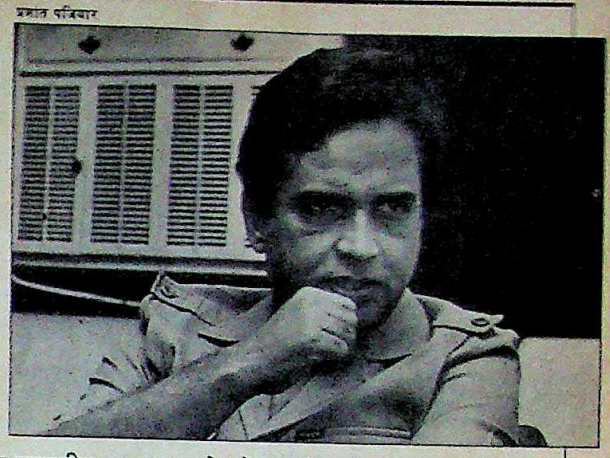

लैब के लिए जरूरी कच्चे माल एन-पाराफीन पर सीमा शुल्क में कटौती की गई. इन दोनों चीजों का आयात सिर्फ रिलायंस ही करती है.

पिछले जून में एक विवादास्पद फैसला करके सरकार ने रिलायंस को रिफाइनरी का दर्जा दे दिया. इससे उसे पीटीए के लिए जरूरी नेप्था बहुत ही कम सीमा शुल्क पर आयात करने का अधिकार मिल गया. मजेदार बात यह है कि वित्त मंत्रालय पहले रिलायंस की इसी आशय की अर्जी ठुकरा चुका है.

सरकार ने पोलिएस्टर धागा बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक और कच्चे माल डाइमिथाइल टेरीफ्थलेट (डीएमटी) और पीटीए का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को संकेत दिया कि वे रिलायंस द्वारा तैयार किए जाने वाले पीटीए का इस्तेमाल ही करें. कर नीति में इस तरह के बदलाव से रिलायंस की प्रतिद्वंद्वी बांबे डाइंग (जो डीएमटी का इस्तेमाल करती है) को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सरकार के इन फैसलों का कितना असर होगा इसका सही आकलन तो नहीं किया जा सकता लेकिन एक अंदाज के अनुसार रिलायंस को 200 करोड़ रु. का फायदा हुआ है.

इनके अलावा भी कुछ अहम सरकारी घोषणाएं हुई हैं. नवीनतम घोषणा सबसे महत्वपूर्ण है. रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अगले साल से ही लाभांश की घोषणा कर सकती है क्योंकि वह अपने यहां जिन उत्पादों का निर्माण करने जा रही है, उनका आयात और बिक्री कर सकती है. लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी. उसने स्पष्ट किया कि इन उत्पादों का आयात इन्हें इस्तेमाल करने वाले ही कर सकते हैं. फिर पिछले पखवाड़े सरकार ने एकदम रुख बदल दिया. उसने तीन पेट्रोकेमिकल उत्पादों को ओपन जनरल लाइसेंस में रख दिया. यह आयात इन उत्पादों का उपयोग करने या इन्हें बेच देने वाले, दोनों ही कर सकते हैं. इससे अंततः फायदा हुआ रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को.

लेकिन अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि ये फैसले रिलायंस को फायदा देने के लिए नहीं किए गए हैं. पेट्रोकेमिकल्स सचिव एच.के. खां कहते हैं, "हम किसी भी तरह से रिलायंस को मदद नहीं पहुंचा रहे हैं." उन्होंने माना कि सरकार चाहती है कि डीएमटी और पीटीए का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ पीटीए का ही उपयोग करें. लेकिन उनका कहना है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखा जाएगा. खां कहते हैं, "जब रिलायंस भी शामिल हो तब नीतिगत परिवर्तनों पर ज्यादा गौर किया जाता है."

फिर भी कुछ लोगों को संदेह है कि वित्त मंत्रालय ने रिलायंस के ऋणपत्रों के मामले में कुछ ज्यादा ही नरम रुख अपनाया है. 200-200 रु. मूल्य वाले ये बांड तीन चरणों में शेयर में बदले जाएंगे. पहली बार उसी कीमत पर शेयर मिलेंगे. कानूनन कोई नई कंपनी प्रीमियम पर शेयर नहीं दे सकती. लेकिन रिलायंस की इस सहयोगी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में कहा गया है कि ऋणपत्रों के बाद के परिवर्तन, यदि हुए तो सममूल्य पर होंगे और यह फैसला सरकार करेगी. बाजार के जानकार लोगों का मानना है कि कंपनी प्रीमियम जरूर रखेगी. बंबई के एक निवेश बैंकर ने कहा, "ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी को इस सूचना के साथ ऋणपत्र जारी करने की अनुमति मिली हैं कि बाकी परिवर्तन प्रीमियम पर होंगे."

संभव है कुछ अंदेशे सच साबित न हों लेकिन इन सारी बातों से यही जाहिर होता है कि रिलायंस अब विजय पथ पर अग्रसर है. ऑल इंडिया क्रिपर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जमनादास मुरजानी कहते हैं, "मौजूदा नीतियों के चलते रिलायंस इस साल निश्चित रूप से बढ़िया स्थिति में होगी." लगता है कि रिलायंस अपना नाम सार्थक कर रही है.

—आनंद पी. रमन, बंबई में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योग

नई राह, नई मंजिलें

औद्योगिक व्यापारिक जगत में नए क्षत्रपों की तूती

दो साल पहले तक बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे. पर अब उन अनजान लोगों की पहचान बन रही है. उनका औद्योगिक साम्राज्य तेजी से फैल रहा है. इनमें से कुछ भारी-भरकम पेट्रोरसायन और खाद उद्योग लगाने की जुगत भिड़ा रहे हैं तो कुछ जमे-जमाए धंधों पर काबिज होने में जुटे हैं. आइए उद्योगों के इन नए क्षत्रपों से मिलें:

▶ शशिकांत रुइया (43) और रविकांत (38). इन भाइयों ने नाममात्र की पूंजी से ही एस्सार समूह खड़ा कर दिया जो अब समुद्रतटीय निर्माण, जहाजरानी और इस्पात कंपनियों का काम संभालता है. उनकी कामयाबी से प्रभावित होकर हाल में सरकार ने उनसे बीमार चल रही सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी का काम संभालने को कहा था (पर बाद में तय किया कि इसे सिंधिया खुद ही चलाएंगे).

▶ अन्नामलाई चिदंबरम मुथैया (47) के आक्रामक विस्तार अभियान ने मद्रास की उर्वरक और रसायन उद्योग की बड़ी कंपनी साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (स्पिक) को दक्षिण की एक महत्वपूर्ण ताकत बना दिया. यह सौम्य उद्योगपति हाल ही में दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी कूद पड़ा है. उन्होंने कार बनाने वाली कंपनी स्टैंडर्ड मोटर्स में हिस्सेदारी हासिल कर ली है. और अब वे डिटर्जेंट उद्योग लगाने जा रहे हैं.

▶ महेंद्र स्वरूप (68) और उनके बेटे विक्रम (39) और गौरव (31). कंपनियों पर काबिज होने और यहां-वहां पूंजी लगाने की कोशिशों के कारण कलकत्ता के इस व्यवसायी को काफी विरोधी प्रचार का सामना करना पड़ा. (जैसे स्वदेशी पॉलि-टेक्स के लिए उनकी लड़ाई और हाल ही में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज़ में उनके निवेश और कुछ अरसे बाद ही रकम निकाल लेने की वजह से बार-बार सुर्खियों में आते रहे).

▶ बाल-सुलभ छवि वाले लुधियाना के उद्यमी अभय ओसवाल (39) ने अपने उद्योगपति परिवार से नाता तोड़ा और पिछले छह वर्षों में खेती पर आधारित उद्योगों का एक खास मुनाफा कमाने वाला समूह खड़ा कर दिया उन्हें यकीन है कि किसी धंधे पर काबिज हो जाना आगे बढ़ने का सबसे आसान रास्ता है. ओसवाल ने राजस्थान के कोटा में डीसीएम रसायन और खाद कारखाने तथा बंबई में यूनियन कार-

भरतिया भाइयों को यकीन है कि इस साल उनकी कंपनी की कुल बिक्री 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 225 करोड़ रु. पर पहुंच जाएगी. और नई परियोजनाएं तीन साल में रफ्तार से चलने लगेंगी

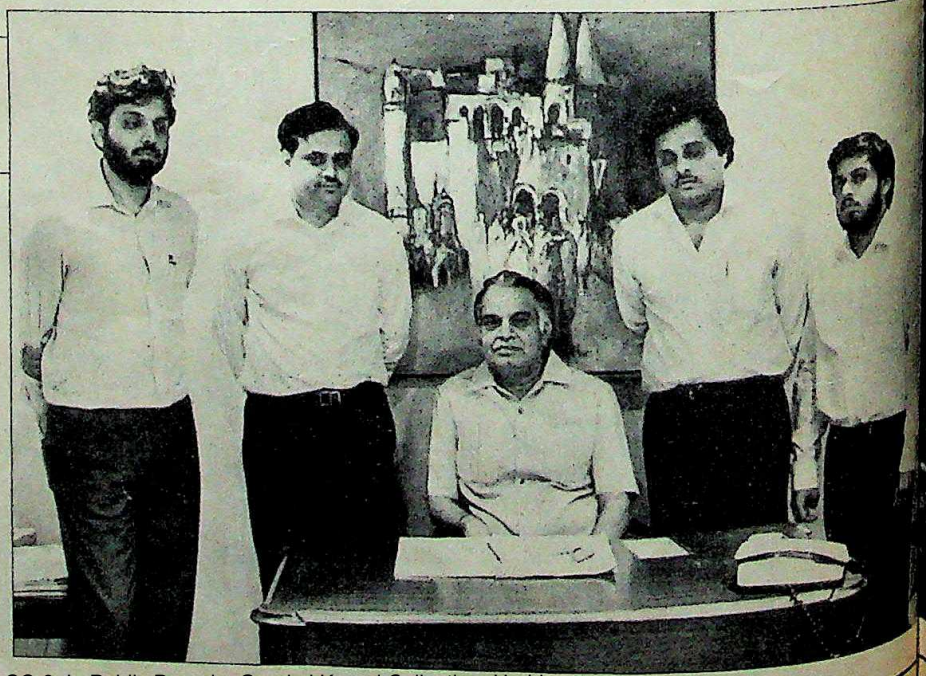

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ESSAR

शशि और रवि रुइया की एस्सार शिपिंग और एस्सार गुजरात कंपनियां गुजरात के हजीरा में गैस आधारित ब्रिकेटेड स्पंज आयरन परियोजना शुरू करने जा रही हैं. जल्द ही ये व्यावसायिक क्षितिज पर कौंधने लगेंगी

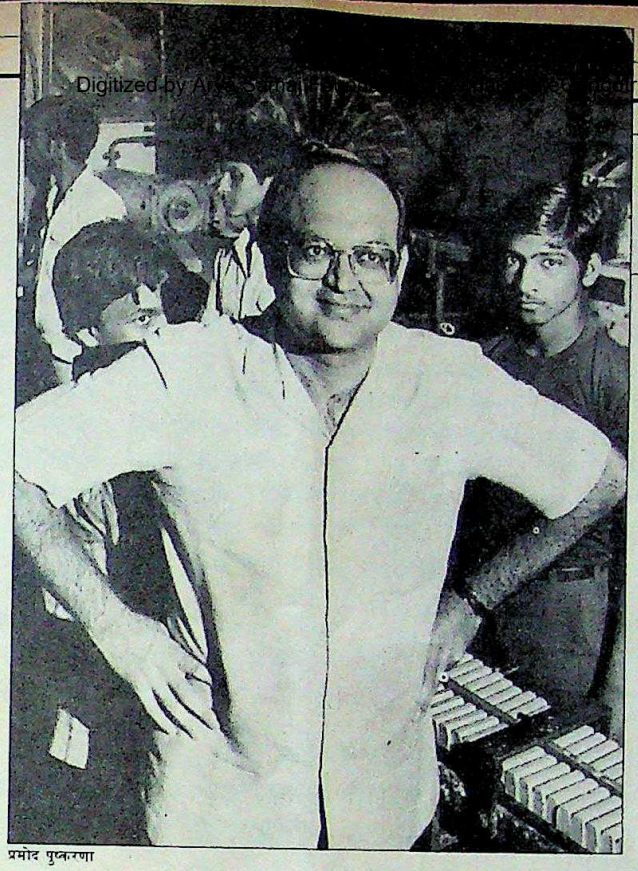

प्रमोद पुष्करणा

अभय ओसवाल ने छह वर्ष पहले अपने उद्योगपति परिवार से नाता तोड़ा और अब वे खेती पर आधारित उद्योगों के 360 करोड़ रु. के विशाल समूह के मालिक हैं. वे मानते हैं किसी धंधे पर काबिज हो जाना आगे बढ़ने का आसान रास्ता है

बाद के बंद पड़े पेट्रोरसायन को हासिल करने की कोशिश की है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 840 करोड़ रु. की लागत से उसके परियोजना लगाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए भी उन्होंने सरकार के पास अर्जी दी है.

▸ भरतिया बंधु—हरि, श्याम, उमा और अजय भी कारबाइड संयंत्र के दावेदार हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, कीटनाशक और रीइनफोर्सिंग एजेंट (सिलिका) के नए उपक्रमों में हाथ आजमाने जा रहे भरतिया भाइयों को उम्मीद है कि अब रसायनों और स्टील के तारों के धंधे में उनके समूह का सितारा बुलंद होगा.

ऐसे कई उद्यमी हैं. जैसे एच.एस. जालान के दुग्ध उत्पाद और इंस्टैंट काफी मिश्रण बाजार में ब्रुक ब्रांड और फूड स्पेशलिटीज जैसे धुरंधरों से टक्कर ले रहे हैं. मुथैया और स्वरूप जैसे उद्योगपति हालांकि कुछ अरसे से जमे हुए हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब उनकी तूती बोलने जा रही है.

अब रुइया बंधुओं को ही लीजिए. 100 करोड़ रु. से भी ज्यादा की बिक्री, 120 करोड़ रु. जमा-पूंजी रखने वाली और गुजरात के हजीरा में गैस आधारित ब्रिकेटेड स्पंज आयरन परियोजना शुरू करने जा रही उनकी कंपनियां—एस्सार शिपिंग और एस्सार गुजरात—जल्द ही व्यावसायिक क्षितिज पर कौंधने लगेंगी.

दूसरे भी जोर-आजमाइश को तैयार हैं. भरतिया भाइयों को यकीन है कि इस साल उनकी कंपनी की कुल बिक्री 100 करोड़ रु. से बढ़कर 225 करोड़ रु. पर पहुंच जाएगी. और कंपनी की नई परियोजनाएं (कीटनाशक, प्लास्टिक के लिए आधारभूत निर्माण) तीन साल में पूरी रफ्तार से चलने लगेंगी. भरतिया बंधुओं की योजना है कि अपने उद्यमों के विस्तार पर अगले पांच साल में 500 करोड़ रु. खर्च किए जाएं.

मुथैया और ओसवाल भी पीछे नहीं हैं. उन्होंने भी अपनी बिक्री 1000 करोड़ रु. तक पहुंचने की भविष्यवाणी की है. 'स्पिक' ग्रुप तो 1000 करोड़ रु. की बिक्री के करीब पहुंच ही गया है. मुथैया का दावा है कि

मैवल दास

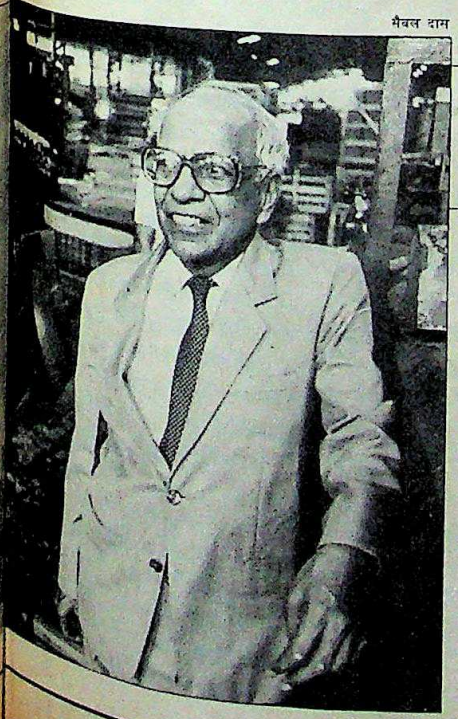

PAHARPUR

महेंद्र स्वरूप की पहाड़पुर कूलिंग टावर्स कंपनी का 80 करोड़ रु. के कूलिंग टावर्स बाजार के लगभग आधे पर कब्जा है. लेकिन दूसरे क्षेत्रों में पांव पसारने का भूत उन पर भी सवार है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SPIC

ए.सी. मुथैया के विस्तार अभियान ने मद्रास की 'स्पिक' को दक्षिण की एक महत्वपूर्ण ताकत बना दिया है. मुथैया को उम्मीद है कि 1992 तक उनकी बिक्री दुगुनी बढ़कर 1000 करोड़ रु. हो जाएगी

श्याम टेकवानी

1992 तक 'स्पिक' ही 5,000 करोड़ रु. की अपनी बिक्री दुगुनी कर लेगी.

ओसवाल का कहना है कि यदि कोटा का संयंत्र और कारबाइड प्लांट उनकी कंपनियों के हाथ लग गया तो उनके समूह की इस साल की अनुमानित बिक्री 360 करोड़ रु. 1990 तक 1000 करोड़ रु. हो जाएगी. यदि ये दोनों कारखाने न भी मिले तब भी उर्वरक परियोजना तो है ही. उन्हें यकीन है कि सरकार उनकी कंपनियों को लाइसेंस दे देगी. ओसवाल बताते हैं, "हमने सरकार को लिखित गारंटी दी है कि हम पैसे के लिए सरकारी खजाने के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे." सरकार इस प्रस्ताव को ठुकरा सकती है या नहीं कहना मुश्किल है. सरकार की 'हां' होने पर भी ओसवाल पीवीसी और कास्टिक सोडा संयंत्र लगाकर पेट्रोरसायन के रास्ते पर जा सकते हैं.

पेट्रोरसायन, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इनमें से ज्यादातर उद्यमियों ने धावा बोला है. हरि भरतिया (31) स्वीकार करते हैं, "हम पेट्रोरसायन और साथ ही रसायन के क्षेत्र में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं." इसकी वजह स्पष्ट है. इन दोनों उपक्रमों में एक साथ कूद पड़ने से प्रतिद्वंद्वियों से बढ़त तो मिलती ही है, बिक्री भी तेजी से बढ़ जाती है. ओसवाल कहते हैं, "उपभोक्ता वस्तुओं से संभावनाएं सीमित हैं. इनकी बिक्री 70 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. तक तो ले जाई जा सकती है पर उसे 1000 करोड़ रु. नहीं किया जा सकता है." ओसवाल नहाने का साबुन भी बनाते हैं.

मुथैया भी इसी श्रेणी में आते हैं. उनकी कंपनियों ने सिंथेटिक डिटर्जेंट के कच्चे माल लीनियर एल्काइल बेंजिन (लैब) और हाइब्रेड सर्विस उद्यमों में तकरीबन 120 करोड़ रु. लगाए हैं और साथ ही कोठारी इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन से कास्टिक सोडा संयंत्र भी हासिल कर लिया है. वे 30 करोड़ रु. की डिटर्जेंट परियोजना पर भी काम कर रहे हैं.

लेकिन महेंद्र स्वरूप का मामला अलग है. 50 फीसदी शेयरों के साथ उनकी पडाड़पुर कूलिंग टावर्स का 80 करोड़ रु. के कूलिंग टावर्स बाजार में सिक्का चल रहा है. लेकिन दूसरे क्षेत्रों में पांव पसारने का भूत उन पर भी सवार है. सिंथेटिक झोलों और लचीली पैकिंग के उत्पादन में हाथ आजमा रही उनकी तीन कंपनियों की बिक्री करीब 65 करोड़ रु. तक पहुंच गई है. 1990 तक बिक्री का यह आंकड़ा 100 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है. स्वरूप तो अपनी सालाना रिपोर्ट तक नहीं बांटते. गौरव स्वरूप बताते हैं, "हमारी सालाना रिपोर्ट गिने-चुने लोगों को ही दी जाती है. सारे शेयर परिवार में ही रहते हैं." फिर भी यह साफ है कि स्वरूप ने पहाड़पुर से इतना मुनाफा कमाया है कि अगर वे चाहें तो बाजार की बाकी कंपनियों से दो-दो हाथ कर सकते हैं. उन्होंने 500 से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर खरीदे हैं. महेंद्र स्वरूप बताते हैं, "हमारा कोई भी निवेश कुल पूंजी की एक फीसदी से ज्यादा नहीं है." पर वे स्वदेशी में 25 फीसदी हिस्सेदारी और केएसबी पंप के सबसे बड़े भारतीय शेयर होल्डर होने की बात स्वीकार करते हैं.

ये नए उद्यमी पुराने अलंबरदारों से अलग किस्म के हैं. औद्योगिक क्षितिज पर तेजी से उभरते ये सितारे कृषि-रसायन, पेट्रोरसायन जैसे कमाऊ धंधों और उन सेवाओं में हाथ डाल रहे हैं जो अब तक आयातित की जाती थी.

स्वरूप का जीवन उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी से शुरू हुआ. कलकत्ता में आरा मिल खरीदने से पहले तक वे एसडीएम के पद पर थे. स्वरूप बताते हैं, "मैं यह सोचकर परेशान हो उठता था कि 55 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते मेरा क्या होगा." यही चिंता उन्हें धंधे में ले आई और उन्होंने वाटा व हिंदुस्तान लीवर को लकड़ी की पेटियां सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया. पहाड़पुर ने जब सिंदरी उर्वरक संयंत्र के कूलिंग टावर्स के लिए लकड़ी सप्लाई की तो वे कूलिंग टावर्स के धंधे में भी कूद पड़े.

मद्रास में रुइया परिवार अयस्क निर्यात का धंधा करता था. दोनों भाई कॉलेज में ही थे कि 1969 में उनके पिता का देहांत हो गया. अब वे पुश्तैनी धंधे से नाता तोड़ समुद्री निर्माण के धंधे में कूद पड़े.

वैसे ओसवाल पहली पीढ़ी के उद्यमी नहीं कहे जा सकते. उनके पिता और भाई ओसवाल ऊनी मिल समूह के कर्ताधर्ता हैं और वे खुद भी एक दशक तक इसके प्रबंध निदेशक रह चुके हैं. लेकिन विरोधी लोगों से पैसा इकट्ठा करने के सवाल पर उनका विवाद हुआ और उन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया. छह साल पहले तक उनके पास उत्तराधिकार में मिले छह छोटे साल्वेंट संयंत्र थे जिनकी बिक्री 3 करोड़ रु. के आसपास थी. महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए अभय ओसवाल ने पुनः पूर्ति लाइसेंस हासिल करके जेनरेटर और खाद्य तेल आयात करने का धंधा शुरू कर दिया. ओसवाल एग्रो मिल और बिंदल एग्रो केमिकल के अध्यक्ष ओसवाल ने तब इस धंधे से हासिल पैसे को उत्पादन में लगा दिया. चालू हालत की कई इकाइयां (एक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वनस्पति उद्योग, इंडियन एक्सफ्लोसिव का लो-डेंसिटी पॉलिथीन संयंत्र तथा पंजाब में एक चीनी मिल) हासिल कर लीं. हाल ही में उन्होंने संयुक्त क्षेत्र में ओसवाल एग्रो फूरेन नाम से राइस मिलिंग कंपनी शुरू की है.

लेकिन कामयाबी का कोई इकलौता, अचूक यंत्र नहीं है. हर किसी ने अपनी राह से इसे हासिल किया है. जैसे रुइया बंधुओं ने ऐसे उद्यमों में हाथ डाले जिनके उत्पाद या सेवाएं आयात का विकल्प थे. (दरअसल उन्हें डर था कि उन पर उद्योग हथियाने वाले व्यापारी का बिल्ला न लग जाए). नरेंद्र रुइया कहते हैं, "हमने एक ही राह यानी आयात के विकल्प वाले क्षेत्रों में हाथ आजमाने की." भरतिया बंधुओं ने प्रतिद्वंद्विता वाले धंधों को किनारे रख दिया. सबसे बड़े श्यामसुंदर भरतिया कहते हैं, "हमारी रणनीति हमेशा ही यह रही है कि सबसे कम प्रतिद्वंद्विता वाले क्षेत्रों की पहचान करो और खाली जगह भर दो."

स्वरूप ने एकदम अछूते क्षेत्र (तब कूलिंग टावर्स आयात किए जाते थे) में पांव पसारे और जल्द ही बाजार में छा गए. ओसवाल ने अच्छे-खासे चल रहे उद्योगों को हथियाने की रणनीति अपनाई. फिर उन्होंने जनता से बटोरी गई रकम इन उद्योगों में लगाई और तकनीक लाकर उत्पादन बढ़ाया. दूसरी तरफ मुथैया ने उत्पादन तक पहुंचने से पहले बड़ी सावधानी से कच्चे माल पर पकड़ कायम की.

इन पांचों ने पांव पसारने के लिए हर मौके का फायदा उठाया तो कुछ ने चोटी पर पहुंचने की कोशिश में अनैतिक तरीके भी अपनाए. कुछ को अपने संपर्कों से फायदा मिला. जैसे मुथैया को राजनेताओं से दोस्ती रखने वाले के रूप में जाना जाता है. एम.जी. रामचंद्रन के साथ ही विपक्षी नेता एम. करुणानिधि से भी उनका संपर्क रहा. अब केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह भी उनके उतने ही गहरे दोस्त हैं जितने तमिलनाडु प्रदेश इंका के अध्यक्ष जी.के. मूपनार. इसलिए कोई हैरत नहीं कि उन्होंने पेट्रोरसायन परियोजना के हर लाइसेंस के लिए तमिलनाडु में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी और सरकारी मिल्कियत वाले मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड को पछाड़ दिया.

जहां लाइसेंस नेताओं की मर्जी पर बंटते हों, वहां यह सब अस्वाभाविक भी नहीं. पर इसमें कोई संदेह नहीं कि तमाम विपरीत माहौल के बावजूद ये लोग अपना औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करने और उसे फैलाने में कामयाब हो गए.

—आनंद पी. रमन के साथ पलकुन्नयु जी. मथाई और ब्यूरो रिपोर्ट

स्कूटर कंपनियां

अपने अपने दावे

परीक्षण के नतीजे परदे में

बात पांच महीने से भी पहले की है. 78 दिनों में उन्होंने 60 से ऊपर शहरों की यात्रा की. पर भारत में पहली बार उपभोक्ता उन्मुख इस स्कूटर परीक्षण के नतीजे अभी भी रहस्य बने हुए हैं क्योंकि देश के तीन बड़े स्कूटर निर्माता इसे लेकर अपनी बेहतरी का रौब गालिब करने में जुटे हैं. इस अल्फा लैप टेस्ट को एक नई ऑटो-मोबाइल परीक्षण फर्म अल्फा मोटर कंपनी ने आयोजित किया था जिसकी नींव हिमालयन रैली के संस्थापक अध्यक्ष नाजिर हुसैन ने रखी है. तीन स्कूटर—बजाज सुपर, एलएमएल वेस्पा एनवी और काइनेटिक होंडा 27 फरवरी को बंबई से इस यात्रा पर रवाना हुए थे.

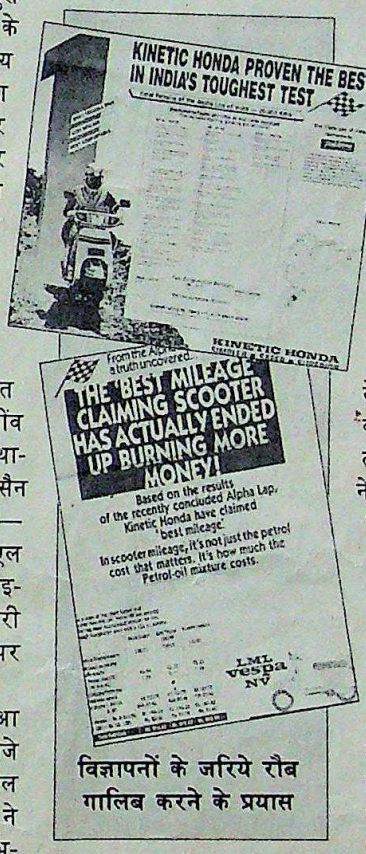

विज्ञापनों के जरिये रौब गालिब करने के प्रयास

लफड़ा तब खड़ा हुआ जब हैदराबाद तक नतीजे घोषित होने के बाद अप्रैल में काइनेटिक होंडा ने जोरदार विज्ञापन अभियान छेड़ दिया, जिसमें उसने अपने अव्वल होने का दावा किया. पुणे की फिरोदिया कंपनी का कहना था कि बेहतर इंधन किफायत और सबसे सुविधाजनक सवारी के मामले में उसके 100 सीसी स्कूटर ने 150 सीसी के दो प्रतिद्वंद्वी स्कूटरों से बाजी मार ली है.

कानपुर की एलएमएल कंपनी ने भी तुरंत आस्तीनें चढ़ा लीं. एलएमएल ने अपने एक विज्ञापन में कहा कि "बेहतर इंधन किफायत का दावा करने वाले स्कूटर पर ही दरअसल सबसे ज्यादा खर्च आया है." विज्ञापन के मुताबिक पेट्रोल की लागत ही नहीं, बल्कि 'पेट्रोल-मोबिल मिश्रण की लागत' को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए. इसलिए एलएमएल ज्यादा किफायती है. यह बात आंशिक तौर पर ही सही है क्योंकि एलएमएल का दावा दिल्ली में पेट्रोल की कम कीमत पर आधारित है.

इन दावों के बीच बजाज ऑटो चुप्पी साधे रही. लेकिन एक वित्तीय दैनिक में छपे किसी बेनाम सर्कुलर के हवाले से बजाज सुपर के सर्वश्रेष्ठ रहने का दावा किया गया.

अब हुसैन कहते हैं, "इन सारे विज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों में मनमाफिक तथ्य जोड़े गए जो हालांकि गलत नहीं हैं पर पूरी तस्वीर पेश नहीं करते. सही बात सामने लाने के लिए हम एक पुस्तिका प्रकाशित करने की सोच रहे हैं." दुनिया का हर निर्माता ऑटो-मोबाइल परीक्षण के अच्छे पहलुओं पर ही जोर देता है. अपनी कंपनी के विज्ञापन अभियान की आलोचना के जवाब में काइनेटिक होंडा के बाजार सेवा प्रबंधक एस. मूरजानी कहते हैं, "अगर हम पूरी तस्वीर पेश करते तो काइनेटिक होंडा और बेहतर दिखाई पड़ता. पर हम उन्हीं नतीजों को इस्तेमाल करना चाहते थे जो निर्विवाद हैं."

बजाज ऑटो के महाप्रबंधक (मार्केटिंग) अरुण पांडे को लगता है कि परीक्षण एक लाख किलोमीटर से ज्यादा पर होना चाहिए था और हर उत्पादक के एक से ज्यादा स्कूटर लिए जाने चाहिए थे. बराबरी वाले स्कूटरों का मुकाबला भी होना चाहिए था. उनका दावा है कि 100 सीसी का बजाज कम इंधन खपत के मामले में काइनेटिक होंडा से निश्चय ही आगे निकल जाता.

परीक्षण के विचार की इन तीनों उत्पादकों ने हिमायत की थी. उन्होंने पूरे रास्ते में इंजीनियरों की सेवाएं दीं और पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए. तीन लाख रुपए की लागत वाले अल्फा लैप का प्रायोजन रेमंड वूलन मिल ने किया था. हुसैन कहते हैं, "उत्पादकों को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक आंकड़े मिल गए हैं." पर सवाल यह है कि क्या वे इन्हें इस्तेमाल करने के लायक हो गए हैं?

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भविष्य निधि

हक पर हमला

कई कंपनियों पर भारी बकाया

रॉयल कलकत्ता क्लब, समाचार पत्र कंपनियां—अमृत बाजार पत्रिका और युगांतर लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, भारत ब्रेक्स ऐंड वॉल्वस, ब्राइटवेट ऐंड कंपनी और जेसॉप ऐंड कंपनी जैसी संस्थाएं चूक करने वालों की पश्चिम बंगाल सरकार की सूची में क्यों हैं?

इन सबने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की रकम जमा नहीं की है. ऐसा करने वाली सिर्फ ये कंपनियां ही नहीं हैं. पिछले साल प. बंगाल की 1227 कंपनियों ने भविष्य निधि कोष में अपने हिस्से के 98 करोड़ रु. जमा नहीं कराए. देश भर में भविष्य निधि की कुल बकाया रकम 171 करोड़ रु. है और प. बंगाल में कुल बकाया रकम इसकी 50 फीसदी बैठती है. भविष्य निधि बकाया वाले राज्यों में प. बंगाल का स्थान सबसे ऊपर है.

कानून के मुताबिक कर्मचारियों का पैसा सरकार या किसी ट्रस्ट के पास न जमा कराना फौजदारी अपराध है. लेकिन प. बंगाल स्थित कंपनियों के प्रबंधकों को इसका खौफ नहीं. हाल में यह प्रवृत्ति ज्यादा तेजी से उभरी है. 1981 में भविष्य निधि का बकाया 20.34 करोड़ था जबकि 1987 में 97.67 करोड़ रु. हो गया.

प. बंगाल के भविष्य निधि आयुक्त अमित कुमार मुखोपाध्याय स्वीकार करते हैं, "हालत चिंताजनक है." भाकपा सांसद गुरुदास दासगुप्त कहते हैं, "हमारी यूनियनों के उग्र होने की बड़ी बातें कही जाती है फिर भी हम प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया जमा न कराने का विरोध करने में असफल रहे हैं."

समस्या को जानते हुए भी राज्य सरकार इस मामले में अक्षम नजर आती है. श्रममंत्री शांति घटक कहते भी हैं, "हम लाचार हैं." सरकार ने अपनी बला न्यायपालिका के गले मढ़ दी है. कई कंपनियों ने अदालतों से स्थगनादेश पा लिए और बाद में सरकार से समझौता कर लिया.

प. बंगाल में यह समस्या विकराल होने का एक कारण तो स्पष्ट है. जूट, कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों का सूरज अस्ताचल को जा रहा है. नतीजतन पिछले पांच वर्षों में राज्य के उद्योगों में यह बीमारी

कार्टून: अजीत नैनन

बढ़ गई है. भविष्य निधि जमा नहीं करने वाली ज्यादातर कंपनियां इन्हीं क्षेत्रों की है. मुखोपाध्याय बताते हैं, "भविष्य निधि का 60 फीसदी बकाया अकेले जूट उद्योग में ही है." ज्यादातर जूट कारखानों में तालाबंदी चल रही है. ऐसे में बकाया रकम कभी वसूल भी हो पाएगी इसमें संदेह ही है.

भविष्य निधि की रकम जमा न करने वालों में अब चाय कंपनियां भी आ गई हैं. दार्जिलिंग की राजनैतिक समस्याओं का खामियाजा भुगततीं इन कंपनियों की माली हालत खस्ता हो गई है. इसलिए भविष्य निधि की रकम जमा न करने का विकल्प उनके लिए सबसे आसान हो उठा है.

कंपनियों के प्रबंधक इस मामले में कानून का उल्लंघन करने के आदी हो गए दिखते हैं. सरकारी अधिकारी यह भी बताते हैं कि प्रबंधकों ने मजदूरों को भविष्य निधि रकम छोड़ने के लिए बाध्य किया.

मिसाल के तौर पर टीटागढ़ जूट मिल के प्रबंधकों ने 18 महीने से चल रही तालाबंदी तब तक खत्म नहीं की जब तक कि मजदूर कार्यशील पूंजी के रूप में 15 लाख रु. जमा करने को राजी नहीं हो गए. स्पष्ट है कि मजदूरों के सामने पूंजी जुटाने का अकेला बड़ा स्रोत था भविष्य निधि कोष से कर्ज उठाना. दासगुप्त कहते हैं, " इस तरह प्रबंधक मजदूरों की पहले से जमा रकम भी लूट लेते हैं." लेकिन टीटागढ़ जूट मिल के प्रबंध निदेशक पूरन सिंह थापा कहते हैं, "हमारे इरादे नेक हैं. हमने अपने मजदूरों के साथ करार किया है कि हम निश्चित रूप से उनकी रकम लौटाएंगे."

एक और मामले में न्यू सेंट्रल जूट कंपनी ने मजदूरों को बकाया राशि के बदले अपने शेयर पकड़ा दिए. यह कतई उचित नहीं है. लेकिन कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "मजदूर और प्रबंधक कंपनी को चालू रखने पर राजी हैं. फिर किसी और को आपत्ति क्यों है?"

मजदूर संघ भी विरोध नहीं कर रहे हैं. वे बेरोजगार मजदूरों की नाराजगी का सामना नहीं कर सकते.

हाल तक सरकार और अदालतें इस समस्या पर ध्यान नहीं देती थीं. पिछले साल भविष्य निधि कोष के क्षेत्रीय आयुक्त ने 2800 मामले सरकार को दिए लेकिन सिर्फ 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया. अदालतें ऐसे मामलों में उदारतापूर्वक स्थगन आदेश दे देतीं या अग्रिम जमानत मंजूर कर लेती थीं.

लेकिन अब अदालतें सख्त रुख अपनाने लगी हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने नाम ने छापने का आग्रह करते हुए बताया कि हाल में अदालत ने एक ऐसी लुब्रिकेटिंग उपकरण कंपनी के प्रबंधक की अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी जिसने मजदूरों के वेतन से भविष्य निधि के नाम पर पांच लाख रु. तो काट लिए पर रकम जमा नहीं कराई. इसी तरह अदालत ने अमृत बाजार पत्रिका समूह को भी भुगतान के आदेश दिए हैं. इस कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "कुछ वित्तीय परेशानियां थीं इसलिए हम रकम नहीं जमा कर पाए. लेकिन अदालत के आदेश पर हमने 1987 के शुरू तक का बकाया जमा करा दिया है."

राज्य सरकार अब संबंधित कानून कड़े करने की योजना बना रही है. यह व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य निधि चुकता न करने वाली कंपनी का निजी कोष और प्रबंधकों की जायदाद जब्त कर ली जाए. इसमें कुछ समय लग सकता है. लेकिन सबसे दुखदायी बात यह है कि 'मजदूरों के राज्य' में मजदूरों के हक की रकम भी मारी जा रही है.

—कमलजीत रक्षित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टेल्को

पहियों की तेजी

व्यावसायिक वाहनों के बाजार में

कामकाजी लोगों का वाहन मानी जाने वाली पिकअप वैन जाने क्यों अब तक भारतीय सड़कों से नदारद थी. यह मुख्यतः अमेरिकी वाहन दुनिया भर में खूब चलता है. बहरहाल, अब भारतीय सड़कों पर पिकअप वैन धूम मचाने वाली हैं. टाटा-मोबाइल के पहिये तेजी से घूमने लगे हैं.

टाटा समूह की भारी-भरकम कंपनी टाटा इंजीनियरिंग ऐंड लोकोमोटिव कंपनी (टेल्को) ने पिछले महीने डीजल वाली पिकअप वैन 'टाटामोबाइल 206' को बाजार में उतारा. दो टन तक भार ढो सकने वाली इस खूबसूरत गाड़ी की बुकिंग तो एक दिन में ही बंद हो गई लेकिन बंबई में टेल्को की 43वीं वार्षिक आम बैठक में जिस डीजल वाली टाटाइस्टेट स्टेशन वैगन का प्रदर्शन किया गया उसने और सनसनी पैदा कर दी. साफ था कि टेल्को अब सिर्फ हल्के व्यावसायिक वाहनों के बाजार में ही अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाना चाहती, बल्कि बड़ी कारों के बाजार में भी धूमधड़ाके से उतरने की तैयारी कर रही है.

सुमंत मुलगावकर

टेल्को अब सिर्फ विदेशी बाजार के लिए विशिष्ट बेंज व्यावसायिक वाहन बनाने के लिए डायमलर-बेंज के साथ तकनीकी और गठबंधन करने की कोशिश कर रही है. बेंज ने जिन दो विदेशी कंपनियों को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे करीब 6000 ट्रक बनाने के लिए चुना है उनमें टेल्को भी एक है.

वैसे भी 1987-88 टेल्को के लिए एक जबरदस्त सफल वर्ष था जिसमें उत्पादन और बिक्री का नया रिकार्ड बना और पिछले साल के बुरे कामकाज की कालिख भी धुल गई. बिक्री 1400 करोड़ रु. से ऊपर पहुंच गई और मुनाफा पिछले साल के 3 करोड़ रु. से बढ़कर 27 करोड़ रुपए हो गया. कंपनी ने करीब 56,000 गाड़ियां बेचीं जिनमें हल्के व्यावसायिक वाहनों की संख्या 8,830 थी. इस वाहन के देसी बाजार में उसका हिस्सा करीब 25 फीसदी हो गया. इस साल 15,000 हल्के व्यावसायिक वाहन बेचने का लक्ष्य है जिसमें कम-से-कम 3,000 टाटामोबाइल होंगे.

टेल्को के 83 वर्षीय अध्यक्ष सुमंत मुलगावकर कहते हैं, "अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिन क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है, उनमें पिकअप वैन भी एक है. भारत के लिए यह चीज भले ही नई हो, पर यह चलेगी जरूर. हमें उम्मीद है कि विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग होगी."

'आधा ट्रक-आधा कार' वाले ये टाटा-मोबाइल वाहन अभी तो सिर्फ पश्चिमी भारत और दिल्ली में ही मिल रहे हैं लेकिन अगली जुलाई तक ये देश भर में मिलने लगेंगे. इसकी कीमत 1.63 लाख (दमन में) से 1.84 लाख रु. (बंबई में) के बीच है. एक लीटर डीजल में यह 15 किलोमीटर दूरी तय करता है.

अगले कुछ महीनों में ही टेल्को के स्टेशन वैगन की बुकिंग भी शुरू होगी. इसमें भी टाटा-मोबाइल वाला इंजन ही लगा है. अगली जुलाई तक पेट्रोल से चलने वाला पैसेंजर सैलून भी आ जाने की उम्मीद है. मुलगावकर कहते हैं, "पिकअप पहला चरण है और इस्टेट दूसरा. तीन वर्ष की अवधि में हम अंतिम चरण—टाटा कार—पर पहुंच जाएंगे."

जब राजीव सरकार ने ऑटोमोबाइल लाइसेंस नीति को उदार बनाने की घोषणा की थी तो टेल्को ने जापानी कंपनी होंडा के सामने गठबंधन प्रस्ताव रखा था. लेकिन जब सरकारी स्वीकृति नहीं मिली तो देसी कार तैयार करने पर जोर लगाया गया. दो वर्ष की मेहनत और 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पुणे में टेल्को के इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (ईआरसी) ने मर्सिडीज की तरह दिखने वाली कार बनाई. डीजल से चलने वाली 1,948 सीसी क्षमता की यह गाड़ी बहुत शोर नहीं करती. 'इंडियन ऑटो जर्नल' के संपादक गौतम सेन कहते हैं, "दो साल के अंदर किसी गाड़ी की रूपरेखा तैयार करने से लेकर उत्पादन तक पहुंचना एक विश्व रिकार्ड ही है."

चूंकि डीजल व्यावसायिक वाहनों के लिए कम कीमत पर बेचा जाता है, इसलिए सरकार बड़े पैमाने पर डीजल कार बनाने को प्रोत्साहन नहीं देगी. इसलिए ईआरसी अब पेट्रोल इंजन विकसित करने पर लगा है.

हल्के व्यावसायिक वाहन बनाने के लिए जहां अन्य कंपनियों ने जापान की टोयोटा, मित्सुबिशी, निसान और माजदा जैसी कंपनियों से गठजोड़ किया, वहीं टेल्को ने खुद अपने यहां पहले 5.3 टन वजन ढोने वाले '407' और फिर 6 टन वजन ढोने वाले '608' हल्के व्यावसायिक वाहनों का उत्पादन किया. जापानी तकनीक वाले वाहनों को बाजार में टिकने में तो मुश्किल हो रही है मगर टेल्को की गाड़ियां मजे से हल्के व्यावसायिक वाहन बाजार पर छाती जा रही हैं. जापानी मुद्रा येन का मोल बढ़ने से जापान की सहयोगी कंपनियों पर बोझ बढ़ गया है. दरअसल, सालाना 40,000 गाड़ियां बनाने वाले हल्के व्यावसायिक वाहन बाजार में पुरानी कंपनियों की ही चलती है. इस बाजार में बजाज टेंपो का हिस्सा 34 फीसदी, टेल्को का 22 फीसदी और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा का 15 फीसदी है.

अगर टेल्को तरक्की के इसी रास्ते पर चलती रही तो वह जल्दी ही निश्चित रूप से मोटर उद्योग के शूरवीरों में शरीक हो जाएगी.

—एम. रहमान

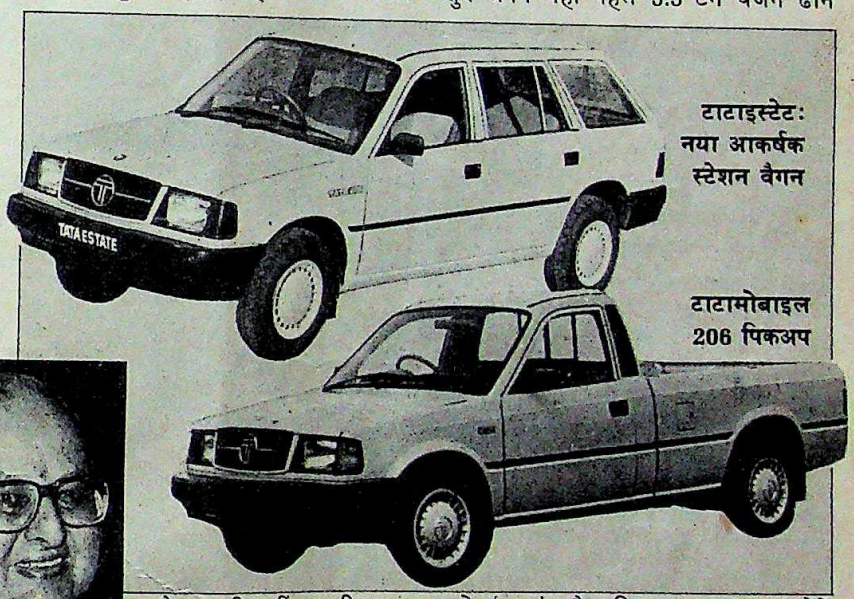

टाटाइस्टेट: नया आकर्षक स्टेशन वैगन

टाटामोबाइल 206 पिकअप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

उत्साह बरकरार

बड़ी योजनाओं से उम्मीदें बंधीं

पिछले कई हफ्तों से शेयर बाजार के जानकार भविष्यवाणी कर रहे थे कि बाजार के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है. लेकिन बाजार में आए उफान का एक कारण था कुछ सरकारी रियायतों की उम्मीद. लेकिन सरकार ने रियायतें नहीं दी तो क्या होगा, यह सवाल भी जानकारों को बुरी तरह मथ रहा था.

पिछले पखवाड़े इसका जवाब भी मिल गया. थोड़ी नरमी के साथ खुलने के बावजूद शेयरों की कीमत धीरे-धीरे चढ़ती गई और इकॉनॉमिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक 254.9 से बढ़कर 267.7 पर पहुंच गया. यह वृद्धि पांच फीसदी हुई. इस दिन सूचकांक वर्ष के सर्वोच्च बिंदु 272.2 से सिर्फ पांच अंक ही नीचे था.

यह वृद्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि सरकार से रियायतों की आस पूरी

चार्ट: बी.के. शर्मा

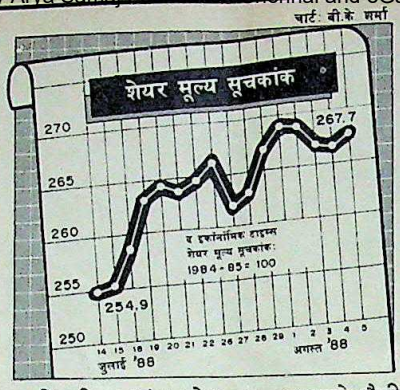

नहीं हुई. लाभांश को कर मुक्त करने जैसी कोई रियायत न देने की घोषणा वित्त राज्य-मंत्री एडुआर्डो फेलेरिओ ने संसद में की.

इस घोषणा से आई मामूली मंदी के बाद शेयर बाजार अपने दम पर उठ खड़ा हुआ. इसमें सिर्फ अच्छे मानसून से ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी कंपनियों के अच्छे कामकाज की उम्मीद से भी मदद मिली. साउथ इंडिया विस्कोस, टाटा इलेक्ट्रिक और क्लोराइड इंडिया जैसी कंपनियों ने पिछले साल से बेहतर या वैसे ही परिणामों की घोषणा की. जिन शेयरों (कोलगेट, बांबे डाइंग, एमआरएफ और वाम आर्गेनिक) का कारोबार बहुत नहीं हुआ उनमें भी वृद्धि हुई.

एक बार फिर यूनिट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं ने ही बड़े पैमाने पर खरीद शुरू की. लेकिन यह भी स्पष्ट था कि इस खरीद को दूसरे बड़े खरीदारों से समर्थन नहीं मिल रहा था. शेयर बाजार के कुछ जानकार लोगों का कहना है कि कई नए निर्गमों की उम्मीद को देखते हुए निवेशकों ने अपने शेयर नहीं निकाले और अब वे मुनाफा कमा रहे हैं.

बंबई शेयर बाजार में कर्मचारियों और अधिकारियों का झगड़ा न सुलझने से भी बाजार के उत्साह में कुछ बाधा आई. इस कारण पिछले पखवाड़े के कुछ दिनों सिर्फ घंटे-घंटे भर के लिए कारोबार चला.

वैसे रिलायंस, सेंचुरी और टिस्को जैसे नामी-गिरामी शेयरों ने ही बाजार का असली रुख तय किया. लार्सन ऐंड टुब्रो के शेयर ने भी सबका ध्यान खींचा. इस कंपनी पर कब्जे की कोशिशों की खबर के बीच इसके शेयरों की पूछ अचानक बहुत बढ़ गई.

बाजार रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के 519 करोड़ रु. के ऋणपत्र आने की उम्मीद में बैठा है, ऋणपत्र 22 अगस्त को जारी होंगे और इसमें निवेशक कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, इस पर भी बाजार का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करेगा.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 5.8.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	47.50	30.25	47.50	6.50 +
एसोसिएटेड सीमेंट	265.50	128.50	250.00	19.00 +
एटलस कोप्को	63.50	33.50	52.00	—
एशियन पेंट्स	175.00	128.75	157.50	2.50 —
बजाज ऑटो	520.00	187.50	261.25	15.00 +
बड़ौदा रेयॉन	282.50	140.00	235.00	22.50 —
बाटा इंडिया	77.25	50.50	65.50	1.00 —
भारत फोर्ज	147.00	101.00	127.00	—
बिरला जूट	47.00	32.25	43.75	3.25 +
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	35.00	—
बॉम्बे डाइंग	159.50	94.00	115.50	1.50 —
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	86.00	5.00 —
ब्रुक ब्रांड	98.00	75.00	85.50	1.00 —
सेंचुरी स्पिनिंग	901.25	617.50	892.50	2.50 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	64.00	0.50 —
कोलगेट	228.50	160.00	220.00	5.00 +
सायनामिड	52.00	33.00	41.00	1.00 —
डीसीएम	47.50	28.00	37.37	4.38 —
डनलप	86.50	69.50	71.00	2.75 —
ईआई होटल्स	54.00	38.00	49.00	1.00 —
एस्कार्ट्स	57.00	37.00	48.75	1.25 —
फिनोलेक्स केबल्स	435.00	260.00	272.50	155.00 —
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	93.50	126.25	0.25 —
गरवारे नाइलोन	43.50	20.00	41.50	1.50 —
जी.ई. शिपिंग	33.75	20.80	28.75	1.37 —
गुजरात स्टेट फर्टि.	146.00	75.00	138.00	—
ग्रासिम इंडिया	111.00	81.50	108.00	2.00 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	93.00	5.00 +
हिंदुस्तान सिबा	520.00	332.50	510.00	5.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	81.25	—
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	69.50	0.50 +
हिंदुस्तान मोटर्स	29.25	15.80	25.90	1.50 +
आई.ई.एल.	43.75	31.00	34.50	1.50 —
इंडियन आर्गेनिक	27.00	15.00	24.00	2.50 —
इंडियन रेयॉन	75.00	46.00	68.00	6.50 —
इंड्राल	223.75	133.75	165.00	3.75 —
इंगरसॉल-रैंड	335.00	205.00	270.00	2.50 +
आई.टी.सी.	46.75	30.00	44.00	2.00 —
जे.के. सिंथेटिक्स	74.00	45.50	66.50	1.75 +
काइनेटिक इंजी.	285.00	161.25	220.00	7.50 —
किर्लोस्कर क्युमिस	59.00	48.00	56.00	0.50 +
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	320.00	52.50 +
लारसन-टुब्रो	122.00	75.50	119.00	19.50 +
लिप्टन	67.00	52.00	63.50	1.50 +
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	12.00	3.50 —
मदुरै कोट्स	77.00	59.00	71.00	2.00 +
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	48.50	59.00	0.50 —
मिल्क फूड	152.50	72.50	145.00	12.50 —
मोटर इंडस्ट्रीज	630.00	447.50	590.00	17.50 —
मुकुंद आयरन	97.00	72.50	83.00	4.50 —
नेशनल आर्गेनिक	525.00	390.00	495.00	35.00 +
निरलॉन	16.00	5.00	8.50	1.25 —
ओरके सिल्क मिल्स	51.00	17.00	26.25	4.25 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	161.25	175.00	10.00 —
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	37.00	24.50	30.00	0.50 —
फाईजर	79.50	50.00	59.50	3.50 —
प्रीमियर ऑटो	39.50	23.00	33.00	0.50 +
रैनबेक्सी	120.00	70.00	76.00	0.25 —
रेमंड	96.00	41.50	49.50	0.50 +
रॉकिट ऐंड कोलमैन	227.00	175.00	213.00	—
रिलायंस इंडस्ट्रीज	231.00	69.00	202.50	12.00 —
शॉ वैलेस	132.00	50.50	60.00	5.00 +
श्रीराम फाइबर्स	62.50	32.50	51.50	3.25 —
सीमेंस इंडिया	80.00	56.00	69.50	2.50 —
एसकेएफ बैयरिंग्स	1541.00	1058.00	1475.00	105.00 +
स्पिक	60.25	23.50	51.00	2.75 —
टाटा स्टील	907.50	568.75	821.25	12.50 +
टेल्को	701.00	340.00	690.00	35.00 +
वाम आर्गेनिक	103.00	75.00	88.50	1.50 —
विम्को	24.00	11.00	20.50	2.75 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	11.4683	11.3458
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.0823	1.0700
बहरीन	दीनार	1	37.2486	37.1486
बांग्लादेश	टका	100	45.5036	45.4522
कनाडा	डालर	1	11.8447	11.7228
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0011	1.9805
मिस्र	पौंड	1	6.1594	6.1086
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.2910	2.3246
हांगकांग	डालर	1	1.8072	1.0872
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0880	0.0828
ईरान	रियाल	100	19.9592	19.8632
इटली	लीरा	100	1.0400	1.0318
जापान	येन	100	10.9051	10.6278
केन्या	शिलिंग	1	0.7790	0.7368
कुवैत	दीनार	1	51.3660	51.2992
मलेशिया	डालर	1	5.4037	5.3483
मारीशस	रुपया	1	1.0400	1.0200
नेपाल	रुपया	1	0.6309	0.6000
हालैंड	गिल्डर	1	6.7336	6.6639
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7900	0.7400
सिंगापुर	डालर	1	6.9673	6.8858
स्पेन	पेसो	1	0.1200	0.1000
श्रीलंका	रुपया	1	0.4430	0.4005
स्वीडन	क्रोना	1	2.0999	2.0783
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.1233	9.0273
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1415	0.1200
थाईलैंड	बहत्त	100	55.7526	55.6622
ब्रिटेन	पौंड	1	24.3279	24.1896
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	14.2552	14.1143
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.8312	3.8991
सोवियत संघ	रूबल	1	16.2822	16.2122
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	7.2280	7.5358

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 5.8.88.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली

रक्त से सना हुआ प्रेम

मासूम बच्चों की हत्या से राजधानी में भारी जनरोष

किसी दोहरे हत्याकांड पर शायद ही कभी इतना बवाल हुआ हो. अखबारों ने कई दिनों तक विस्तार से इसे छहने पन्ने पर तो छापा ही, संपादकीय स्तंभों में भी इसका उल्लेख होता रहा.

इन निर्मम हत्याओं पर लोगों का ऐसा ध्यान जाना स्वाभाविक ही था. दो सलोने मासूम—छह साल का सनी और उसकी साढ़े तीन साल की बहन शिखा हत्यारे का शिकार हुए थे. पर लोग इस बात पर चौंके कि भरी दोपहरी में दिल्ली के एक सार्वजनिक पार्क में की गई इन हत्याओं की साजिश का इलजाम बच्चों की खूबसूरत मां पर लगाया गया. इसके बाद 25 साल की इंदु अरोड़ा रातोरात दुश्चरित्रता का पर्याय बन गई. लगता है पुराने पड़ोसी 22 वर्षीय अजीत सेठ के साथ इंदु के अंतरंग संबंध लोगों के दिलो-दिमाग पर छाए हुए थे.

पुलिस के अनुसार 24 जून को अजीत ही दुलार पड़कर आते बच्चों को बगीचे में ले गया. वहां उसने दोनों बच्चों को रस्सी से घोंटा और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी.

इंदु-अजीत के रिश्तेदारों का भी मानना है कि दोनों में प्रेम संबंध थे. पुलिस का कहना है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि दोनों का प्रेम-व्यापार अजीत द्वारा हाल ही में खरीदे गए घर में चला करता था. आसपास के होटलों में भी उन्होंने कई रातें बिताई. रंगरेलियों की इन खबरों ने ही लोगों को ज्यादा भड़का दिया. 33 साल की अभिभाषक वंदना श्रीनिवासन कहती हैं, "बच्चों की हत्या की साजिश भले ही उसने न रची हो लेकिन इस आदमी के साथ अवैध संबंध बनाने की दोषी तो वह है ही. इन संबंधों को उसने बच्चों पर भी जाहिर कर दिया."

न्यायाधीश ने भी ऐसी ही दलील दी. आठ पन्ने के आदेश में इंदु की जमानत नामंजूर करते हुए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जसपाल सिंह ने उसके जुर्म की ओर इशारा किया, "उसके प्रेमी ने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी पर वह जरा भी विचलित नहीं हुई. उसने बच्चों का अपहरण कर लिया पर वह शांत बनी रही. तीन घंटे तक उसने बच्चों के पिता को भी उनके गायब होने की सूचना नहीं दी. बच्चों के साथ हादसा हो जाने की खबर से भी वह नहीं घबराई. इसकी वजह यह है कि वह अपने बेटे से नफरत करती थी. वह उनकी जासूसी करता था. अपने पिता तक सब खबरें पहुंचाता था. उसके रास्ते का रोड़ा था. हालात किसी गहरी साजिश का संकेत देते हैं."

इंदु अरोड़ा: अदालत की ओर

लोग इंदु और अजीत को अपराधी मान लें तो कोई आश्चर्य नहीं. लेकिन बच्चों की हत्या के मामले की गुत्थियां अभी अनसुलझी हैं

पुलिसवालों के इस दावे को मिले भारी प्रचार को देखते हुए कि उन्होंने हत्याओं के तुरंत बाद इकबालिया बयान हासिल कर लिए, लोग यदि इंदु-अजीत का अपराध साबित हुआ मान लें तो कोई आश्चर्य नहीं. लेकिन मामले की कई गुत्थियां अभी भी अनसुलझी हैं. मसलन यदि इंदु को बच्चे रास्ते की अड़चन नजर आते थे तो वह उन्हें और 31 साल के पति हरीश को आसानी से छोड़कर जा सकती थी.

इस बात के सबूत हैं कि अजीत उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था. मध्यवर्गीय परंपराओं में पला शांत और स्वाभिमानी अजीत इंदु से संबंध बनाकर मध्यवर्गीय वर्जनाओं को पहले ही तोड़ चुका था. इसी तरह इंदु भी जिसका परिवार उन्नति करते-करते उच्चमध्यम वर्ग के दायरे में आया था. सरकारी स्कूल में पढ़ी इंदु की शादी आठ साल पहले हुई थी. उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना है कि वह शांत और एकांतप्रिय महिला थी, जो बच्चों, खासकर शिखा से बहुत प्यार करती थी. उसकी एक निकट संबंधी का कहना है, "इंदु यदि गुसलखाने में भी जाती तो शिखा उसके पास जाने के लिए दरवाजा थपथपाती रहती." अजीत सेठ का परिवार आठ नवंबर 1986 को पश्चिम विहार में अरोड़ा परिवार के पड़ोस में बी-2/60 नंबर के मकान में आकर बसा था. अजीत के पिता हरी सेठ का कहना है कि दोनों परिवारों में घनिष्ठता पिछले साल मई में बढ़ी, जब पुरानी दिल्ली में कर्फ्यू की वजह से हरीश और अजीत अपनी दुकानों पर नहीं गए. अजीत वीडियो गेम घर ले आया था और दोनों परिवार वहीं जमे रहते.

हरी सेठ कहते हैं, "हरीश को मैं बेटे की तरह ही मानने लगा था." जब भी हरीश की इंदु से झड़प होती—ऐसा अक्सर ही होता था—वह हरीश से अपने साथ खाना खाने का आग्रह करते. अजीत के पिता को लगता है कि इंदु और अजीत में घनिष्ठता इस साल जनवरी में बढ़ी होगी, जब अजीत के अलावा उनका पूरा परिवार कार दुर्घटना के बाद महीना भर मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती रहा था. इंदु प्रायः बच्चों के साथ अकेली रहती थी. उस वक्त अजीत भी अपने घर में अकेला ही था.

उसी दौरान अजीत ने नया घर खरीदने और इंदु के साथ सैर-सपाटे के लिए अपनी स्टेशनरी दुकान की आमदनी पर हाथ साफ किया. अदालत तय करेगी कि क्या अनायास मिली यह दौलत, सामाजिक बंधनों से मुक्ति तथा प्रेम-संबंध ही उन मासूमों की हत्या के कारण बने.

—डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मच्छर

जीते हैं शान से, मारते हैं जान से

सारी दवाएं बेअसर, तमाम उपाय निरर्थक, बढ़त बरकरार

मच्छर हमेशा से मनुष्य के आसपास ही रहा है. यह सभी कीट-पतंगों में सबसे ज्यादा घातक होता है. दुनिया में सबसे अधिक बीमारी भी फैलाता है. मनुष्य इसे खत्म करने के लिए वर्षों से पुरजोर कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो सका है. देश के स्वास्थ्य बजट का एक बड़ा हिस्सा मच्छरों से लड़ाई में ही खत्म होता जा रहा है. मनुष्य से निश्चय ही एक कदम आगे दिखने वाले इस जीव की कहानी बयान कर रहें हैं दो वरिष्ठ संवाददाता ***सिमरन भार्गव*** *और पांडिचेरी से* ***एस.एच. वेंकटरमनी:***

बरसात के साथ ही बिन बुलाया मेहमान मच्छर भी धमाचौकड़ी मचाता लौट आया है. अपनी पूरी फौज के साथ यह शयनकक्षों की गोपनीयता में खलल डालने, रसोई की पवित्रता नष्ट करने और रंगीन शामों का मूड बिगाड़ने के लिए फिर हाजिर हो गया है. प्रकृति का सबसे अनुपयोगी जीव फिर हमारे कर्णद्वार पर दस्तक दे रहा है. मलेरिया शोध केंद्र (एमआरसी) के निदेशक वी.पी. शर्मा कहते हैं, "मच्छरों की उत्पत्ति का यह चरम समय है. इन जीवों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो रही है."

मनुष्य चाहे जितनी प्रगति कर ले पर वह मच्छरों से मुक्ति पाने का कोई भी उपाय नहीं ढूंढ़ पाया है. ठीक हमारी नाक के नीचे, कभी तो उनके ऊपर भी, वे अपनी घृणित कार्रवाइयां अपनी मर्जी से चलाते रहते हैं. तीन जोड़े पैरों, दो जोड़े डैनों और डंकनुमा मुंह वाला यह छोटा आतंकवादी पृथ्वी पर 2.6 करोड़ वर्षों से है. इसकी आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है और समय के साथ यह और ताकतवर होता गया है.

मक्खियों का प्रतिद्वंद्वी मच्छर मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक जीवों में प्रमुख है. दिल्ली के चार्टर्ड एकाउटेंट शिव सरीन की सुहागरात तो छत पर बैठे मच्छरों को तकिया फेंक-फेंककर मारने की कोशिश में ही बीत गई. वे तल्खी से याद करते हैं, "सुबह देखा तो 29 मच्छर मरे हुए थे."

लेकिन वैज्ञानिक परेशान हैं. अब मच्छर पहले की तुलना में ज्यादा साहसी, मोटे-ताजे और ताकतवर हो गए हैं. मारक दवाएं उन पर सदा बेअसर होती रही हैं और मनुष्य को इस परेशानी से निबटने के लिए लगातार नई और खर्चीली दवाओं को ईजाद करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के उपनिदेशक डॉ. आर. राजगोपाल ने कहा, "बाघ और हाथियों का वंश-नाश किया जा सकता है क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता कम है. पर मच्छरों से मुक्ति पाना असंभव है." मच्छरों के अस्तित्व और उनके पनपने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आनन-फानन में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं.

मच्छरों के बारे में विचित्र किस्से-कहानियां भी प्रचलित हैं. कहा जाता है कि एक दफा भोपाल में मच्छरों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि विधानसभा से विधायक वाक-आउट कर गए. हाल ही में मच्छरों के खिलाफ समूचे एर्नाकुलम शहर ने हड़ताल कर दी. कुछ रहस्यमय कारणों से असमी मच्छर सिर्फ गैर-असमिया और बाहर से आने वालों को ही डंक मारते हैं. ऐसा तो नहीं कि उन्हें आसू (अखिल असम छात्र संघ) ने प्रशिक्षित कर रखा हो!

केरल के कुछ समुदायों में तो शादी से पहले लड़कियों को घुटनों तक साडी उठाकर दिखाना होता है कि कहीं वे फाइलेरिया से पीड़ित नहीं. रोगवाही मच्छरों के काटने से यह बीमारी होती है. यमुना नदी के पास दिल्ली की कालिंदी कॉलोनी में इस कदर मच्छरों की भरमार है कि मुंह खोलते ही दर्जनों मच्छर मुंह में घुस जाते हैं. पर लोगों का मानना है कि सबसे बदतर हालत तो बंगलूर की है. हवाई अड्डे पर उतरते ही लगता है कि वहां कव्वाली हो रही है. हर कोई ताली बजाता हुआ दिखता है. लेकिन दरअसल लोग मच्छर मार रहे होते हैं.

एक बार मनुष्य को लगा था कि वह इस आफत के परकालों पर जीत हासिल कर सकता है. द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरंत बाद डीडीटी ईजाद हुई थी. कीट नियंत्रण के क्षेत्र में यह एकमात्र अहम विकास था. उस समय भारत में मलेरिया महामारी का रूप ले चुका था. हर साल मलेरिया के करीब 75 करोड़ मामले मिलते और 8 लाख लोग मर जाते थे. 1958 में बड़े शोर-शराबे के साथ शुरू हुआ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख रूप से डीडीटी पर ही आश्रित था. इस कार्यक्रम का चमत्कारी असर हुआ. 1965 तक देश में लगभग मलेरिया पर काबू पा लिया गया. करीब 7.49 करोड़ मामलों से मलेरिया खत्म कर दिया गया.

पर उसके बाद जैसे ही मनुष्य ने राहत की सांस लेनी शुरू की, मच्छरों की प्रतिरोधक क्षमता उभर आई. मच्छरों की एक भी प्रजाति का विनाश नहीं किया जा सका है. मलेरिया फिर से उन्हीं इलाकों में फैलने लगा जहां उसे खत्म किया जा चुका था. तभी से मच्छरों और आदमी के बीच अमुविधाजनक शीतयुद्ध चल रहा है. लेकिन आदमी को डर है कि आखिरकार जीत किसकी होगी.

मनुष्य चाहे जितनी प्रगति कर ले पर वह मच्छरों से मुक्ति पाने का कोई भी उपाय नहीं ढूंढ़ पाया है. आज दुनिया में मच्छरों की 3,000 प्रजातियां हैं

जब से सरकार ने घरों में डीडीटी का छिड़काव शुरू किया है, मच्छर अधिक चालाक हो गए हैं. वे बाहर ही आराम फरमाते हैं और भूख लगने पर घर में चले आते हैं. पेट भरने पर लौट जाते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

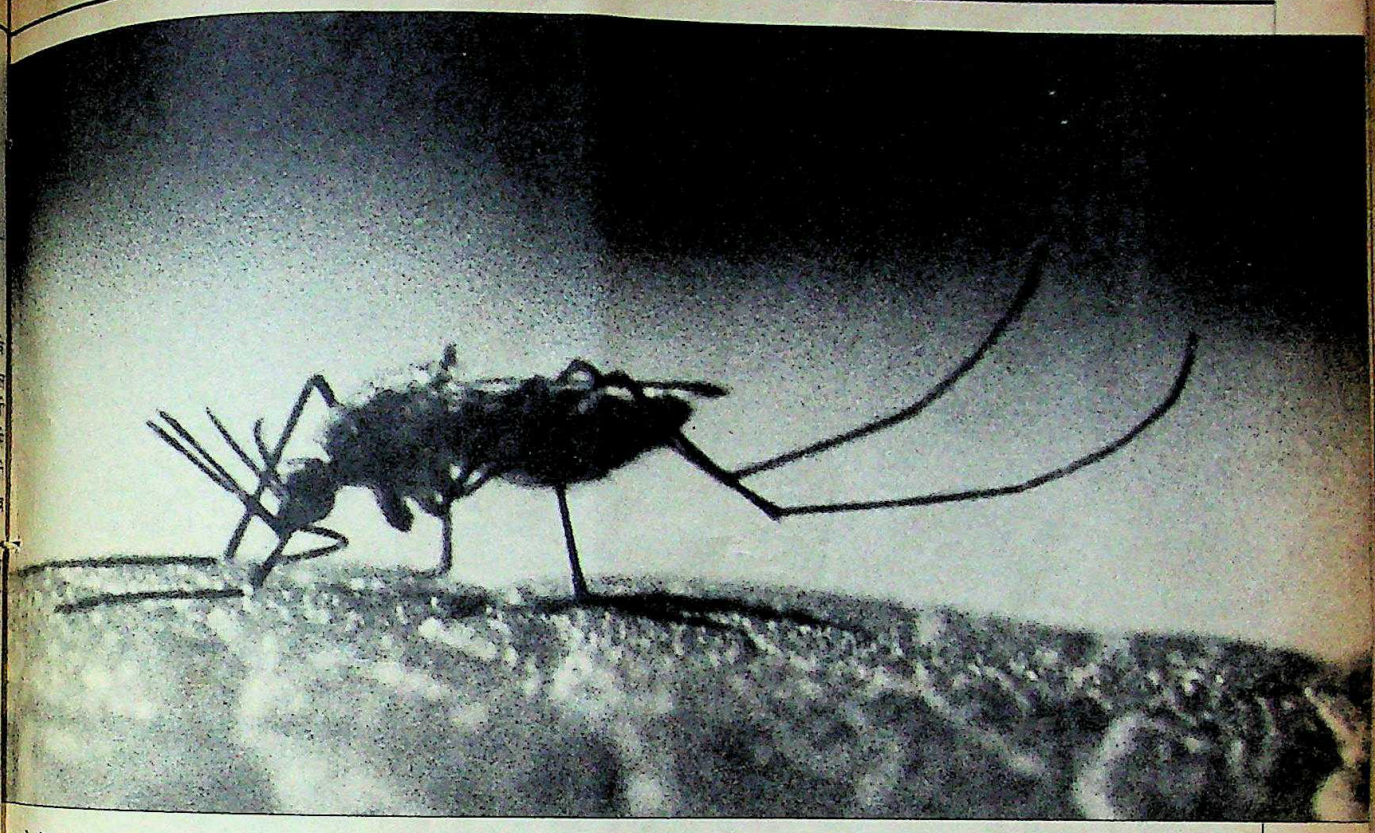

रहते हैं. "मच्छरों में वैज्ञानिकों को मूर्ख बनाने की अगाध क्षमता है. चाहे कितनी भी जहरीली दवा बन जाए, वे उसे नाकाम कर ही देते हैं. हम उन्हें हराने की हर संभव कोशिश करते आ रहे हैं."

विडंबना तो यह है कि आदमी खुद ही मच्छरों की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होता है. वर्मा बताते हैं, "जब भी उन्हें चुनौती दी जाती है, वे और चीमड़ हो जाते हैं" कीटनाशी दवाएं छलनी की तरह काम करती हैं जिससे चीमड़ मच्छर बच निकलते हैं. हर नई कीटनाशी दवा से उनमें प्रतिरोधक जीन आ जाते हैं. इनकी कई प्रजातियों में प्रयोग में लाई जाने वाली तीन कीटनाशी दवाओं— डीडीटी, बीएचसी और मेलॉथिआन की प्रतिरोधक क्षमता आ गई है.

नई-नई दवाओं के आविष्कार से उनके इस्तेमाल की लागत भी बढ़ती जाती है. 10 लाख लोगों को राहत दिलाने के लिए डीडीटी पर 33 लाख, बीएचसी पर 37 लाख और मेलॉथिआन पर 199 लाख रु. खर्च बैठता है. तीसरी कीटनाशी दवाओं पर अनुमानित खर्च 30 से 40 गुना ज्यादा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक शोधार्थी ने कहा, "मच्छर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. वे मनुष्यों की तरह ही अपने को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं."

खून चूसते मच्छर: घातक जीव

फांसीसी इत्रों की तरह खूबसूरत नाम वाले— एनोफेलस, कुलक्स और एडस— ये तीन तिलंगे समूचे मुल्क को खौफजदा किए हुए हैं. आम तौर पर कुलक्स ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. इनको गंदे नाले-नालियों से जीवन-शक्ति मिलती है. एनोफेलस अत्यंत घातक है. यह मलेरिया फैलाता है और पानी की टंकियों, एक जगह जमा हुए जल और बरसाती पानी के जोहड़ों में पैदा होता है.

इन तीनों में एडस सबसे नफासतपसंद होता है. इस पर सफेद धारियां होती हैं. यह प्रजनन के लिए साफ-सुथरी जगहें ही चुनता है. एडस डेंगू और पीत ज्वर का वाहक होता है. पर यह दिन में ही डंक मारना पसंद करता है जबकि बाकी दो किस्म के मच्छरों को रात का साथ ज्यादा भाता है.

मच्छरों का चरित्र दिन-ब-दिन बदलता जा रहा है. उनका एकमात्र मकसद आदमी को ठेंगा दिखाना ही है. जबसे सरकार ने घरों में डीडीटी के छिड़काव की व्यवस्था की है तबसे वे और अधिक चालाक हो गए हैं. अब वे घर के बाहर ही आराम फरमाते रहते हैं और रात्रिभोज के लिए घर में चले आते हैं. पेट भरने पर लौट जाते हैं. दिन में वे गीली, अंधेरी, नम जगहों, अलमारियों के पीछे, गीले कपड़ों और गमले में लगे पौधों पर चुपचाप इंतजार करते रहते हैं.

कई शोधों से पता चलता है कि मच्छरों को हथेली ज्यादा भाती है. कीट वैज्ञानिकों ने पाया है कि उन्हें महिलाएं, काली चमड़ी और कॉर्बन डाई ऑक्साइड भी पसंद है. एडस मच्छर बगल के पसीने की तरफ तो टूट ही पड़ता है. पता नहीं क्या वजह है कि मच्छरों की कुछ प्रजातियां छोटे बच्चों और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को डंसना पसंद नहीं करतीं.

यह मादा मच्छर ही है जो घरों में घुसकर शिकार पर टूट पड़ती है. नर मच्छर शाकाहारी होता है, पौधों के रस से अपना जीवन-यापन करता है और किसी को डंक नहीं मारता. लगता है कि नर मच्छर सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर पैदा होता है— मादा को गर्भधारण कराने के लिए. यह मिशन पूरा होते ही वह छह दिन के भीतर मर जाता है.

सुबह और शाम मच्छरों के झुंड निकलने से पहले तक वातावरण में सन्नाटा छाया रहता है. प्रजनन तभी होता है जब मच्छरों का काले बादलों-सा झुंड आसमान में नृत्य करता दिखता है. मादा मच्छरों के परों के घिसने की ध्वनि सुनकर नर मच्छर कामासक्त हो उठते हैं. झुंड में ही रतिक्रिया संपन्न होती है. फिर नर-मादा झुंड से निकल आते हैं. रतिक्रिया के बाद कुछ समय तक मादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसी मीठी वस्तु का सेवन करती है और फिर रक्त की तलाश में निकल पड़ती है.

वीर्य सेचन के बाद मादा हर तीसरे दिन 80 अंडे देने के काबिल हो जाती है. हर बार अंडा देने के बाद उसकी खूनी प्यास और बढ़ जाती है. एक महीने के भीतर एक मादा 800 बच्चे पैदा कर सकती है. बरसात के बाद सितंबर, अक्तूबर और नवबंर के महीने इसके लिए सबसे उपयुक्त होते हैं. फिर थोड़े विराम के बाद मार्च से मच्छर अपनी संतान-वृद्धि में फिर जुट जाते हैं.

शहरीकरण से भी मच्छरों को प्रजनन की सहूलियत मिल रही है, खासकर उन इलाकों में, जहां मीलों तक खुली नालियां बहती हैं. एक कीटविज्ञानी कहते हैं, "दिल्ली में जहां भी डीडीए की कोई कॉलोनी बनती है वहां प्राय: निश्चित है कि मलेरिया के उपादान भी उभर आते हैं. इससे उन कीटों के जन्म लेने की व्यवस्था भी होती है."

बहरहाल, मच्छरों की कथा कोई हास्य-व्यंग्य नहीं, एक त्रासदी है. यह दुनिया में रोगों का सबसे बड़ा वाहक है. कीटाणुओं से लगने वाले 90 फीसदी रोग यही फैलाता है—मलेरिया, फाइलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू वगैरह. दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कीटविज्ञानी एम.के.के. पिल्लै ने कहा, "मच्छर जनस्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है."

कभी रोगों का सरताज माना जाने वाला मलेरिया बदला भंजाने के लिए फिर आ गया है. इसका खतरा 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सिर पर मंडरा रहा है. स्वास्थ्य के मद में बजट का करीब 40 फीसदी— 170 करोड़ रु. इसी के लिए खर्च होता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल मलेरिया के मामले 18 लाख पर ही रहते हैं पर शोधार्थियों का कहना है कि असली संख्या तो इससे 15 से 20 गुना अधिक है. मलेरिया के दो प्रकार हैं— जून से मध्य अगस्त तक कंपकंपी देकर आने वाले आम मलेरिया 'पी. वाईवेक्स' का समय होता है. अगस्त से घातक स्वायु मलेरिया— 'पी. फाल्सीपारम' का समय शुरू हो जाता है.

सबसे डरावनी स्थिति तो यह है कि ओडीसा, महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों समेत देश के कई हिस्सों में मलेरिया के कीटाणुओं में क्लोरोक्विन (कुनैन) की प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है. डॉक्टरों को इसके लिए अमोडियाक्विन, मेटाकेलफिन और फांसीदर जैसी ज्यादा-से-ज्यादा क्षमता वाली दवाओं का प्रयोग करना पड़ रहा है. पिल्लै कहते हैं, "शायद हम कभी मलेरिया के खिलाफ जंग जीत भी लें लेकिन मच्छरों से पार पाना संभव नहीं."

कई लाख लोग इस कीट के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कबाड़ा हो गया है. तीन दशकों तक डीडीटी छिड़कने के बाद भी इस कार्यक्रम से मच्छरों की किसी एक प्रजाति का नाश नहीं हो पाया है. एक वैज्ञानिक ने कहा, "हम जानते हैं कि उनमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो ही जाती है पर सोच यह है कि उनकी क्षमता विकसित होने से पहले ही हमें उनका खात्मा कर देना चाहिए." यह कार्यक्रम सिर्फ एक नारे के भरोसे टिका है— कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाए. लेकिन यह नारा फिजूल साबित हो रहा है. पांडिचेरी के रोगवाही नियंत्रण शोध केंद्र के निदेशक पी.के. राजगोपालन ने कहा, "कीटनाशी दवाओं पर खर्च की जाने वाली भारी-भरकम राशि का एक हिस्सा भी यदि शहरों और नगरों की हालत सुधारने पर खर्च किया जा सके तो एक दशक में इस स्थिति का स्थायी

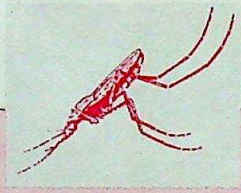

उष्णकटिबंधीय मच्छर पैर के निचले हिस्से का ही रुख करते हैं. कीट-विज्ञानियों ने पाया है कि उन्हें महिलाएं, काली चमड़ी और शारीरिक गंध भी पसंद है

मच्छरों का झुंड: जबरदस्त प्रजनन क्षमता

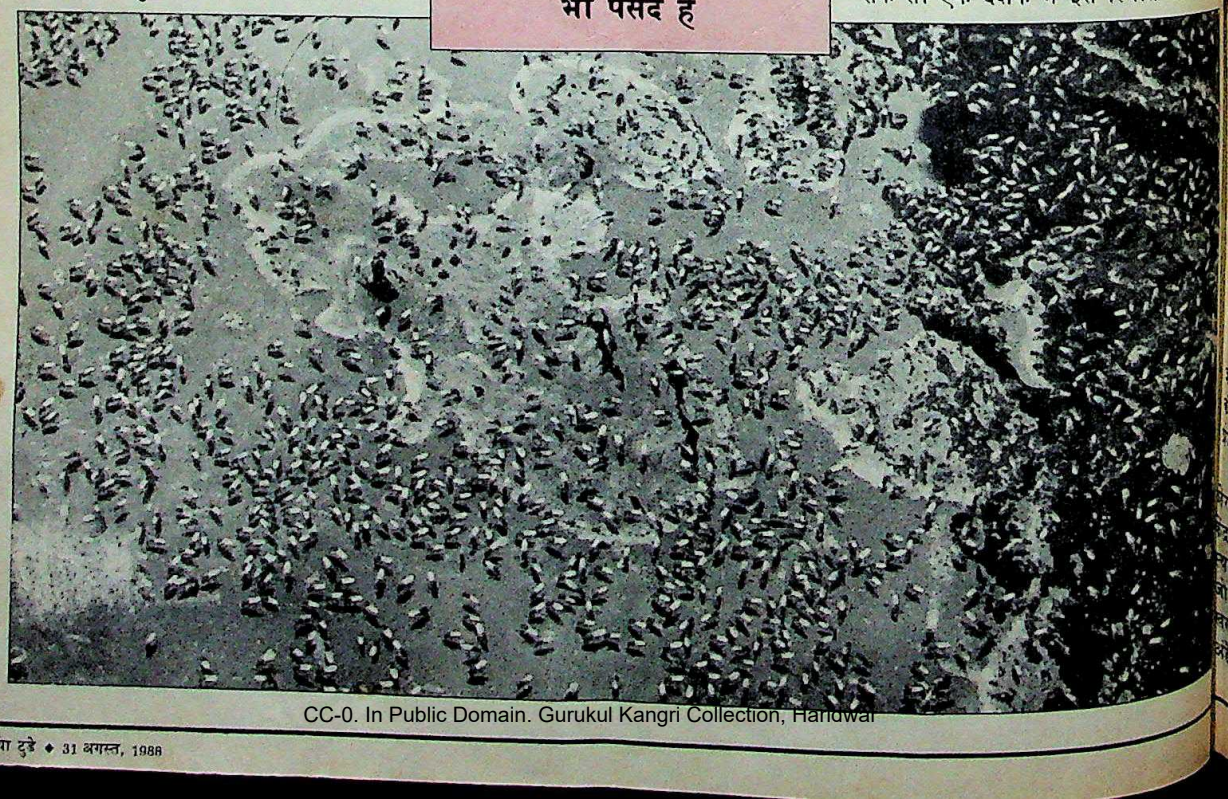

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: भवान सिंह

सड़ा हुआ बदबूदार पानी: मच्छरों का स्वर्ग

मादा मच्छर घरों में घुसकर शिकार पर टूट पड़ती है पर नर मच्छर पौधों के रस से अपना जीवन-यापन करता है और किसी को डंक नहीं मारता

इस निकल आएगा.''

कीटनाशी दवाएं जमीन पर घातक असर डालती हैं. भारतीयों के शरीर में डीडीटी के अवशेष की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है. यह मात्रा भारतीयों से ज्यादा सिर्फ चीनी लोगों में ही है. मेलाथिऑन का धुंआ छोड़ने वाली गाड़ियों पर एक तो बहुत खर्च आता है और फिर यह बेकार भी है. पिल्लै कहते हैं, ''यह एक लंबी लड़ाई है और हमारे तरकश के सभी तीर—कीटनाशी दवाएं कुंद होती जा रही हैं.''

कीटनाशी दवाओं के नाकाम होने से रोगाणु वाहक कीटों पर काबू पाने का कार्यक्रम मुश्किल में पड़ गया है. नतीजतन कई वैकल्पिक रणनीति विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है. अब मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए पर्यावरण संबंधी नियंत्रण पर जोर दिया जा रहा है. रोगवाही नियंत्रण शोध केंद्र और मलेरिया रिसर्च सेंटर को दुरात, केरल और हरिद्वार में कुछ कामयाबी हासिल हुई है. शर्मा ने कहा, ''मच्छरों पर काबू पाना तो सिर्फ सामान्य सूझ की बात है. यदि आप अपने आसपास की जगहों की अनदेखी करेंगे तो इनका प्रजनन होता रहेगा.''

फाइलेरिया से सर्वाधिक पीड़ित केरल के अलप्पुझा शहर में रोगवाही नियंत्रण शोध केंद्र ने सभी नाले-नालियों और पानी जमे स्थानों पर एक खास तरह की मछली डाल दी है. जमे हुए पानी में उगी पिस्तिया नाम की जलपतवार खा जाती है. इसी घास पर मच्छर अंडे देते हैं. मच्छरों के अंडे नाश करने की विधि अहम है क्योंकि एक बार मच्छर उड़ने लगते हैं तो सिर्फ 25 फीसदी मच्छरों को ही मारना संभव हो पाता है.

जैववैज्ञानिक अस्त्र भी आजमाया जा रहा है. यानी मच्छरों के प्राकृतिक दुश्मनों और विषाणुओं को अंडों के नाश के लिए उपयोग में लाना. इनमें मेढ़क, मछली और वैसिलस (एक जीवाणु) का प्रयोग शामिल है. अंडों के नाश के लिए हारमोन, फरमोन (विरोधी हारमोन), कीटाणु-नाशक पौधों को विकसित करने और कीटों के विकास को नियंत्रित करने वाले यंत्रों पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं. इनका एकमात्र मकसद है अंडों को नुकसानदेह मच्छरों में बदलने से रोकना. दूसरे उपायों में नर मच्छरों को निर्वीर्य करके उन्हें मादा मच्छरों के लिए छोड़ देने की विधि पर भी काम चल रहा है. इस तरह मच्छरों में परिवार नियोजन अभियान छेड़ने की योजना बन रही है. लेकिन मच्छरों की कई प्रजातियों में वैसिलस की प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई है.

पर इतनी आफत के बावजूद मच्छरों की वृद्धि कइयों के लिए खुशखबरी भी है. मच्छर भगाने वाली धूपबत्तियों, छिड़काव करने वाली दवाइयों, मलहम और बिजली की बत्तियों के निर्माता बाजार में उतर आए हैं. जाहिर है कि मच्छर अब करोड़ों रुपए के उद्योगों के कारण बन गए हैं.

'मैट' बनाने वाली कंपनी ट्रांसेलेक्ट्रा आज 12 करोड़ रु. का धंधा कर रही है और इसका सारा श्रेय जाता है इसकी गुडनाइट मशीनों को. आजकल 'मैट' का कारोबार करीब 20 करोड़ तक पहुंच गया है. ओडोमॉस बनाने वाले अब वे अतिस्वन विधि विकसित करने पर काम कर रहे हैं.

मच्छरों को अपने से दूर रखने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अब कीटनाशी दवाओं का लेप लगी मच्छरदानी प्रयोग करने की सलाह दे रहा है. लेकिन यह छोटा शैतान भी अपने काम में जुटा हुआ है. शायद कुछ समय बाद वह इन बाधाओं पर भी विजय पा लेगा. इस शताब्दी के अंत तक मच्छरों की 1500 से ज्यादा प्रजातियां कीटनाशी दवाओं की प्रतिरोधी क्षमता हासिल कर लेंगी. राजगोपाल कहते हैं, ''यदि परमाणु युद्ध हुआ तो मनुष्य जाति का तो नाश हो जाएगा पर ये कीट तब भी जीवित रहेंगे.''

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हल्के लड़ाकू विमान

सच होता सपना

राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला में निर्माण की गतिविधियां निर्णायक दौर में

यह लड़ाकू विमान के पायलट का सपना है—इंजन चार सेकेंड में ही काम करने लगे, 500 मीटर तक दौड़ने के बाद हवा में उड़ जाए, 100 सेकेंड से भी कम समय में आवाज से भी तेज गति पकड़ ले और तीन सेकेंड के भीतर 'एल' टर्न. इसमें एक ऐसा राडार हो, जो सामान्य दायरे से बाहर उडने वाले दुश्मन के विमान को खोज निकाले और रात में जमीनी लक्ष्यों का पता लगा ले. और ऐसी मिसाइले हों जो 60 किमी. दूर से ही दुश्मन के विमान को मार गिराए या फिर लेसर किरणों के जरिये दुश्मन के अड्डों की पहचान करे और उन्हें ध्वस्त कर दे.

दरअसल भारत के प्रस्तावित लाइट कंबैट एअरक्राफ्ट (एलसीए)—हल्के लड़ाकू विमान—में अगर कुछ हल्का है तो वह है उसका वजन. पतंगे की शक्ल वाले इस विमान का वजन मुश्किल से आठ टन है और वह बैडमिंटन के कोर्ट पर बड़ी आसानी से उतर सकता है. इस तरह यह विमान बहुत छोटी श्रेणी के लड़ाकू विमानों में आता है. लेकिन जहां तक इसकी क्षमता का सवाल है, यह दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों से टक्कर लेगा. जैसा कि एलसीए कार्यक्रम निदेशक डॉ. कोटा हरिनारायण कहते हैं, "तैयार होने पर यह दुनिया के आधुनिकतम लड़ाकू विमानों में से एक होगा."

लेकिन असल सवाल है यह तैयार कब होगा. फिलहाल हरिनारायण के दफ्तर में गहमागहमी है. इन्हीं सबके बीच हरिनारायण नई दिल्ली से रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के टेलीफोनों का जवाब भी देते रहते हैं. इतनी अफरातफरी की वजह है कि एलसीए अपने संक्षिप्त किंतु उथल-पुथल वाले इतिहास में महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है.

अगले महीने एलसीए योजना पर नियुक्त दल रक्षा मंत्रालय को विमान की प्रारंभिक डिजाइन पेश करेगा. साथ ही इसके निर्माण में जिन एजेंसियों को शामिल किया जाएगा उनका विवरण और खर्च का ब्यौरा भी दिया जाएगा. विमान के ढांचे को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है. इसके त्रिभुजाकार पंखे दुगुनी क्षमता से हवा को चीर सकेंगे. इसके पंखे और पक्षक (पीछे के हिस्से में ऊपर की ओर उभरा हुआ हिस्सा) विशेष कार्बन फाइबर के मिश्रण से बनाए जाएंगे. इसका कॉकपिट भी आधुनिकतम साज-सामान से लैस होगा. इतना ही नहीं इसमें हर मौसम में काम करने वाला शक्तिशाली राडार भी लगा होगा.

एलसीए परियोजना से लड़ाकू विमान बनाने की भारत की क्षमता की कमजोरियां भी उजागर हो रही हैं

इस विमान के लिए सारी तकनीक भारत में उपलब्ध नहीं है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग लेने की योजना बनाई जा रही है. इन सबसे इस विमान पर आने वाला खर्च 600 करोड़ रु. से बढ़कर 2,000 करोड़ रु. हो गया है.

इस परियोजना में लगे देश के 6 संगठनों के 1,000 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में भी जबरदस्त उत्साह है. लगभग 20 साल के निठल्लेपन के बाद देश के निष्क्रिय वैमानिक अनुसंधान संस्थानों को अचानक सक्रिय बना दिया गया है. उनमें

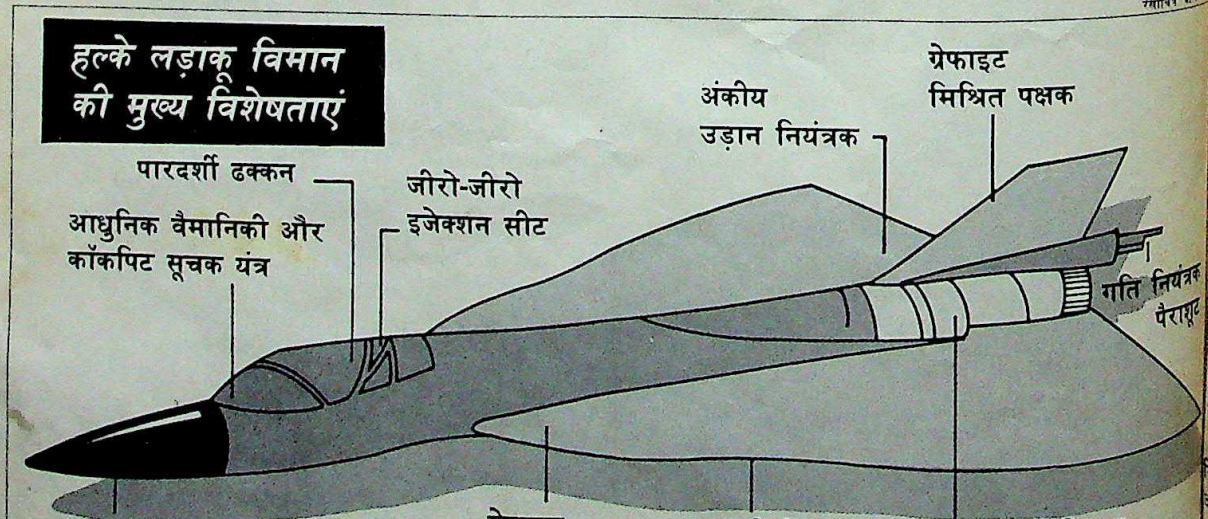

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

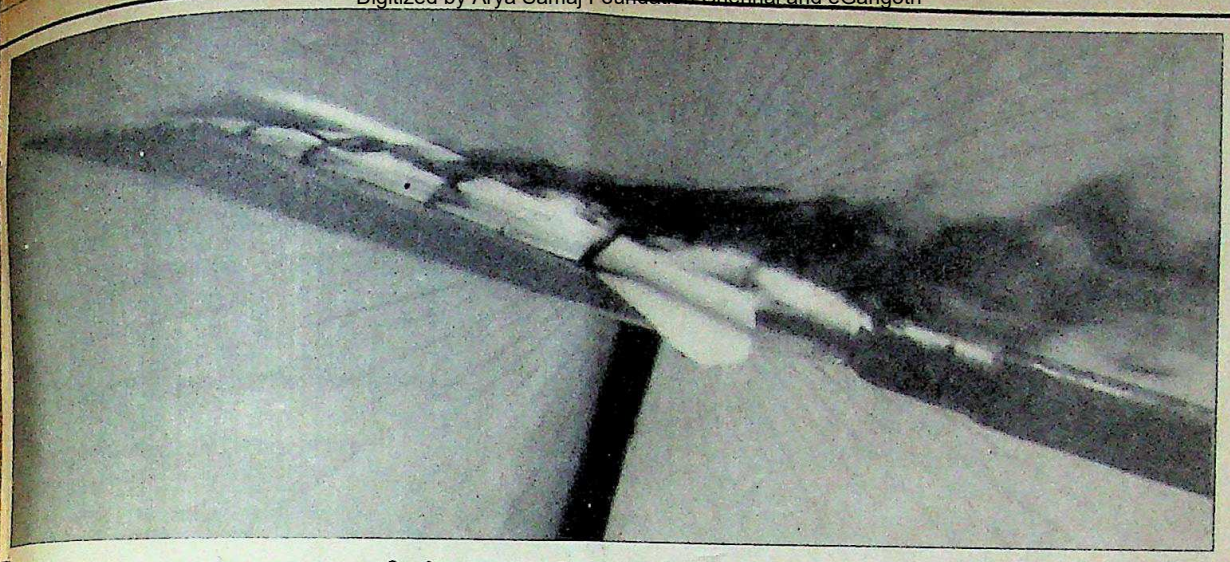

एलसीए का मॉडल और (नीचे) कंप्यूटर से तैयार काल्पनिक मॉडल

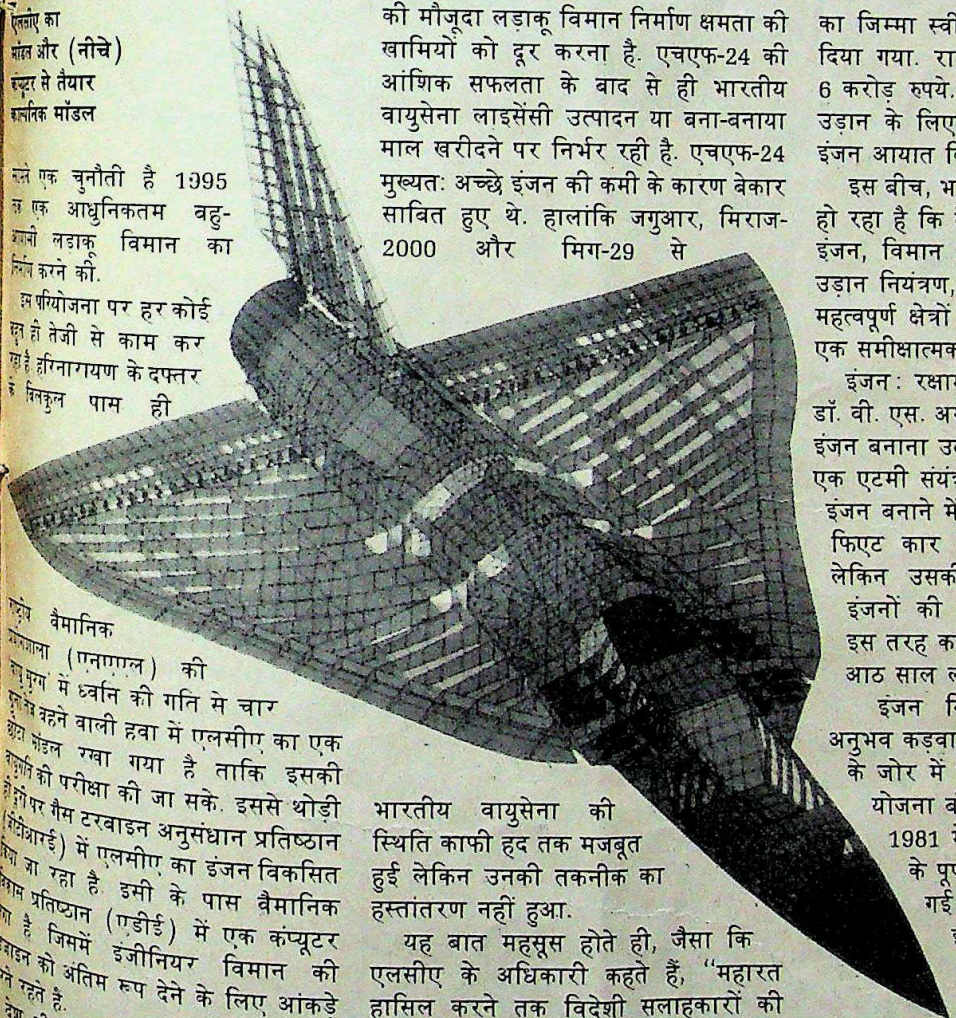

सामने एक चुनौती है 1995 तक एक आधुनिकतम बहु-आयामी लड़ाकू विमान का निर्माण करने की.

इस परियोजना पर हर कोई बहुत ही तेजी से काम कर रहा है हरिनारायण के दफ्तर के बिलकुल पास ही राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला (एनएएल) की 'वायु सुरंग' में ध्वनि की गति से चार गुना तेज बहने वाली हवा में एलसीए का एक छोटा मॉडल रखा गया है ताकि इसकी वायुगति की परीक्षा की जा सके. इससे थोड़ी ही दूरी पर गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) में एलसीए का इंजन विकसित किया जा रहा है. इसी के पास वैमानिक विकास प्रतिष्ठान (एडीई) में एक कंप्यूटर लगा है जिसमें इंजीनियर विमान की डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए आंकड़े भरते रहते हैं.

देश की दूसरी रक्षा प्रयोगशालाओं में विमान में लगने वाले शक्तिशाली राडार, आधुनिक प्रक्षेपास्त्र और उड़ान नियंत्रण प्रणालियां बनाने का काम चल रहा है. एलसीए परियोजना का एक मकसद भारत की मौजूदा लड़ाकू विमान निर्माण क्षमता की खामियों को दूर करना है. एचएफ-24 की आंशिक सफलता के बाद से ही भारतीय वायुसेना लाइसेंसी उत्पादन या बना-बनाया माल खरीदने पर निर्भर रही है. एचएफ-24 मुख्यत: अच्छे इंजन की कमी के कारण बेकार साबित हुए थे. हालांकि जगुआर, मिराज-2000 और मिग-29 से भारतीय वायुसेना की स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई लेकिन उनकी तकनीक का हस्तांतरण नहीं हुआ.

यह बात महसूस होते ही, जैसा कि एलसीए के अधिकारी कहते हैं, "महारत हासिल करने तक विदेशी सलाहकारों की सहायता लेने की जल्दी मच गई" जबकि आलोचक इसे 'बिक जाना' करार देते हैं. पिछले साल फ्रांसीसी कंपनी एविओनिक्स मार्सल दसॉतब्रकेत (एएमडी-बी) को लगभग 12 करोड़ रु. पर परियोजना निश्चयन चरण के लिए सलाहकार बनाया. राडार के विकास का जिम्मा स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को दिया गया. राडार बनाने की लागत होगी 6 करोड़ रुपये. देसी इंजन तैयार होने तक उड़ान के लिए 11 जनरल इलेक्ट्रिक 404 इंजन आयात किए जा रहे हैं.

इस बीच, भारतीय दल इस तथ्य से रूबरू हो रहा है कि देश में उपलब्ध तकनीक जेट इंजन, विमान ढांचे के सामान, वैमानिकी, उड़ान नियंत्रण, राडार और प्रेक्षपास्त्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पुरानी पड़ गई है. एक समीक्षात्मक रिपोर्ट:

इंजन: रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. वी. एस. अरुणाचलम कहते हैं, "एक जेट इंजन बनाना उतना ही कठिन है जितना कि एक एटमी संयंत्र बैठाना." जीटीआरई ऐसा इंजन बनाने में जुटा हुआ है जिसका वजन फिएट कार के इंजन के बराबर होगा लेकिन उसकी क्षमता 2000 कारों के इंजनों की अश्व शक्ति जितनी होगी. इस तरह का इंजन बनाने में कम-से-कम आठ साल लगते हैं.

इंजन निर्माण में जीटीआरई का अनुभव कड़वा रहा है. एचएफ-24 के इंजन के जोर में सुधार के बावजूद वह परियोजना बंद कर देनी पड़ी थी, लेकिन 1981 में उसे उस वक्त जेट इंजन के पूर्ण विकास की अनुमति दे दी गई जब उसने इस तरह का इंजन बनाने की अपनी क्षमता दिखाई लेकिन जब एलसीए दल ने जीटीएक्स 37-14-यू का जायजा लिया तो पाया कि इससे जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं. बाद में इस संस्थान ने एक नया डिजाइन जीटीएक्स-35-वीएस बनाया. संस्थान का दावा है कि वह अनुमति मिलने के बाद 81 महीने में ही इंजन दे देगा. जीटीआरई के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: श्रीनिवास कुमार

निदेशक अरुण प्रसाद कहते हैं, "इस बार खेद जताने का सवाल ही नहीं है. हमने गारंटी मांगी है और इंजन देने का वादा किया है." लेकिन इस बारे में संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि क्या जीटीआरई इंजन दे पाएगा.

विमान का ढांचा: हालांकि भारत पारंपरिक मिश्र धातु वाले विमान ढांचे बनाने में कुशल है लेकिन अब विमान ढांचे की तकनीक काफी आगे निकल चुकी है. अब विमान ढांचा बनाने में कार्बनिक यौगिकों से बनाए गए कार्बन फाइबर मिश्रणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में भारत की क्षमता सीमित है. एनएएल ने हाल ही में एक मिग लड़ाकू विमान के लिए कार्बन फाइबर मिश्रित पूंछ बनाकर इस क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल की है. लेकिन जैसा कि इसके निदेशक प्रोफेसर नरसिंह कहते हैं, "इस तकनीक में महारत हासिल करने में अभी हमें बहुत समय लगेगा."

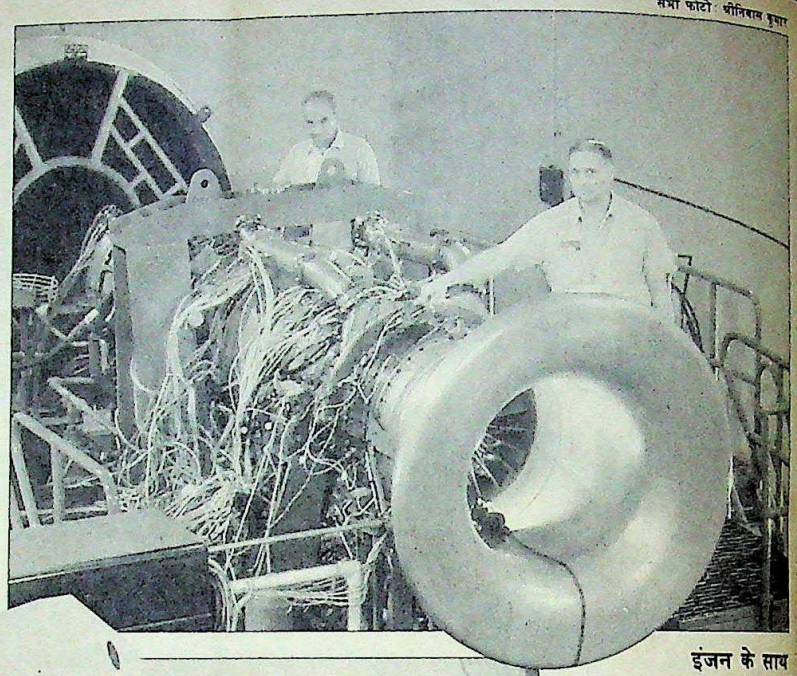

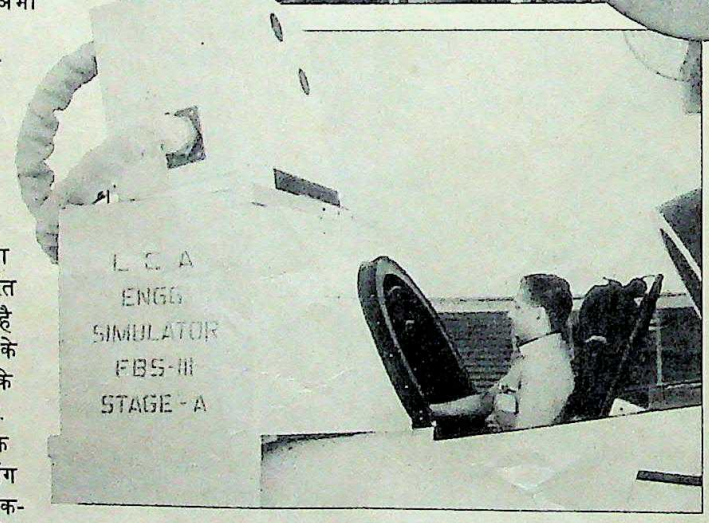

इंजन के साथ प्रसाद; (बाएं) कॉकपिट सिमुलेटर

उड़ान नियंत्रण: हल्के लड़ाकू विमानों के लिए चपलता बहुत ही महत्वपूर्ण है. लिहाजा एलसीए जानबूझकर ऐसा बनाया जा रहा है कि वह अस्थिर रहे. इसकी नियंत्रण प्रक्रिया जटिल होती है और इसे तुरंत सुलझाने की जरूरत होती है इसलिए यह काम अटैची के आकार के एक कंप्यूटर के सुपुर्द कर दिया जा रहा है.

वैमानिकी: यह आधुनिक लड़ाकू विमान का मुख्य अंग है. एलसीए इसकी आधुनिकतम प्रणाली अपनाने की योजना बना रहा है. वैमानिकी के पहले ही कॉकपिट में कई तब्दीलियां कर दी गई हैं. कॉकपिट में पहले कार की तरह कई मीटर लगे होते थे लेकिन यह वैमानिकी का ही कमाल है कि अब आंख की सीध में लगे एक परदे पर ही हर तरह की जानकारी मिल जाती है. इस तकनीक में भी भारत को विदेशी मदद की जरूरत है.

राडार: अति आधुनिक राडारों में अब इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होने लगा है. लड़ाकू विमान नीचे उड़ते हैं और राडारों पर इन्हें खोज पाना मुश्किल होता है. इस समस्या से निबटने के लिए कोहेरेंट पल्स डायलर राडार इस्तेमाल किया जाता है. यह नियमित अंतरालों पर नीचे तरंगें भेजता और विमान की गतिविधि का पता लगा सकता है. एलसीए में इस तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है और उसने इस सिलसिले में एरिक्सन की मदद ली है.

प्रक्षेपास्त्र: भारत को अभी उच्च तकनीक के जो प्रक्षेपास्त्र बनाने हैं उनमें मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र भी हैं. यह तकनीक वैमानिकी और प्रक्षेपास्त्र का मिला-जुला रूप है. विमान में लगा राडार जरूरत पड़ने पर प्रक्षेपास्त्र को उनका सही रास्ता बताता है. इसकी जद 60 किमी की है. एलसीए दल को भरोसा है कि वह जल्दी ही इसमें कामयाबी हासिल कर लेगा.

एलसीए परियोजना में 18 महीने का विलंब किए जाने की कड़ी आलोचना की जा रही है इस बात की पूरी संभावना है कि यह परियोजना 1995 के बाद ही पूरी होगी. हालांकि सरकार ने शुरू में इसके लिए 600 करोड़ रु. मंजूर किए थे लेकिन अब इसके विकास पर लगभग 2,000 करोड़ रु. की लागत आने की संभावना है और अगर निर्धारित बातें ठीक ढंग से न हुईं तो परियोजना बेहद खर्चीली साबित होगी. यह भी महसूस किया जा रहा है कि परियोजना दल जरूरत से ज्यादा ही तकनीक बटोर रहा है. नरसिंह कहते हैं: "हमें अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए और विमान में सुधार करते रहना चाहिए."

इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे कई फायदे हो सकते हैं. कुछ अदृश्य फायदे भी. आत्मनिर्भरता से मदद मिलती है. उसी तरह जैसे कि लाइसेंसी उत्पादन हमेशा दूसरे लाइसेंसी उत्पादन की ओर ले जाता है. इस उद्योग के लिए कई रास्ते खुले हुए हैं. लड़ाई के समय राजनैतिक ब्लैकमेल के आसार कम हो गए हैं, सो तीसरी दुनिया के दूसरे देशों को विमान बेचे जा सकते हैं. लेकिन अभी भी यह तय नहीं है कि यह एलसीए विमान होगा, या जैसा कि अरुणाचलम मजाक में कहते हैं, भारत का नया गड़बड़झाला विमान होगा. —राज चेंगप्पा, बंगलूर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया ओनिडा.
इसे छू पाये तो बस एक ईर्षा भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्षा के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठा ले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'क्यूब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' फ्रंट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के हुक्म में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्षा मंडराती है आसपास। याद रखिये वो सुरक्षा-वाणी: अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शाम उतर आयी थी। अपने भारी-भरकम कर्घे पर खूबसूरत कालीन बुनती अब्दुल्ला की आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। डिज़ाइनदार कालीन में आखिरी टांका लगाते हुए अचानक उन्हें सन् १९७७ की याद हो आयी... जब शाहजहांपुर के कालीन बुनकर बेतरह खस्ताहाल थे। विरासत में प्राप्त हुनर लुप्त हो चला था। उनका सारा उत्साह ही टूट चुका था। उन दिनों ऊनी कालीन का न कोई कद्रदान था, न बाज़ार। तभी आई टी सी त्रिवेणी हैंडलूम्स के माध्यम से उनकी मददगार बनी।

शाहजहांपुर के अब्दुल्ला। इनके हाथों का हुनर इन्हें दो वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पा रहा था।

तभी आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के माध्यम से इनकी प्रतिभा को पहचाना और सम्मान दिया।

निर्यात से पहले, कालीनों की जाँच-परख

इस प्राचीन कला-कारीगरी को पुनर्जीवित करने के लिए, आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स की स्थापना की। कर्नल प्रेम सहगल (आइ एन ए ख्यातिप्राप्त)के समर्पित नेतृत्व में, त्रिवेणी ने प्रतिभाशाली, लेकिन गरीब बुनकरों को कच्चा माल और तकनीकी सलाह देकर उनकी मदद की।

सन् १९७७ में कुल ३५ कर्घे थे। आज ४०० से भी ज्यादा कर्घों पर कालीन बुनाई होती है। बुनकरों का पारिश्रमिक भी ४ रुपए से बढ़कर १५० रुपए प्रति वर्ग फीट हो चुका है। उत्पादन क्वालिटी में भी प्रशंसनीय सुधार हुआ है।

त्रिवेणी की कालीनें अब विदेशों को निर्यात की जाती हैं और ८० लाख रुपयों से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है। आज २५०० से भी अधिक बुनकरों के लिए बेहतर आमदनी, बेहतर जीवन और बेहतर बचत का द्वार खुल गया है। आई टी सी को संतोष है कि यह भारत के कुटीर-उद्योग के विकास में हाथ बंटा रही है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मनुष्य को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य में आई टी सी के प्रयास :

कृषि उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल-बीजों के उत्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार किसानों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी ।

परिवार कल्याण : अपनी विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा आई टी सी परिवार-नियोजन के साधन आसानी से उपलब्ध कराते हुए गांव-कस्बों तक में छोटे परिवार और कई साल के अन्तर में सन्तान-प्राप्ति के लाभ का प्रचार-प्रसार कर रही है ।

भारतीय शास्त्रीय संगीत : कलकत्ते के संगीत रिसर्च अकादमी में परम्परा और तकनीक के गठबन्धन द्वारा आई टी सी ने गुरु-शिष्य परम्परा को जीवित रखा है और देश भर में नयी-नयी संगीत-प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है ।

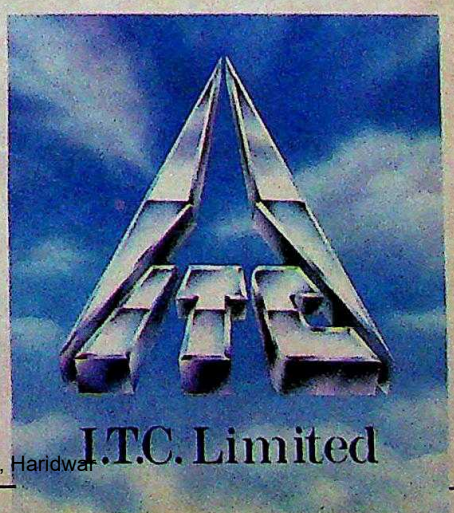

Contract ITC. 40.88 HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिन्टेक्स

पी वी सी दरवाज़े व खिड़कियां

लाए है भारत में टिकाऊ खूबसूरती एवं इंजिनिअरिंग उत्तमता का नया युग

वही श्रेष्ठता, वही ढंग
वही क्वालिटी, वही कार्यकुशलता
जिसने पश्चिमी देशों में तहलका मचा दिया

सिन्टेक्स.... यानी मोल्डेड पॉलीएथीलीन पानी की टंकियों के प्रथम निर्माता अब आपके लिए लाए है एक और क्रांतिकारी उत्पादन. पी वी सी दरवाज़े और खिड़कियां–जिन्होंने पश्चिम जर्मनी, हॉलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, जापान जैसे आधुनिक देशों और न्यूज़ीलैण्ड, दक्षिण आफ्रिका, सऊदी अरेबिया और स्पेन जैसे भारत की तरह गर्म उष्णकटिबंधीय प्रदेशों मे लकड़ी, एल्यूमीनियम व स्टील के दरवाज़े और खिड़कियों को पीछे छोड़कर अपनी उत्कृष्टता की धाक जमा दी है.

विश्वविख्यात प्लस प्लान GmbH वेस्ट जर्मनी के तकनीकी सहयोग से बने हुये सिन्टेक्स पी.वी.सी दरवाज़े और खिड़कियां, आपके लिए लाए हैं टिकाऊ, खूबसूरती और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का ऐसा संगम, जो आज पहले आपके लिए केवल एक सपना था.

टिकाऊ खूबसूरती

इसका खूबसूरत सफ़ेद रूप-रंग समय से पूरी तरह बेअसर है और बरसों ज्यों का त्यों बना रहता है.

- **100% वॉटर-प्रूफ:** न सड़े, न गले, न फूले, न ही टूटे-फूटे.
- **हर मौसम के अनुकूल:** धूप-गर्मी, बरसात या बर्फ़ या समुद्री हवा से बेअसर, न रंग फीका पड़े.
- **देखभाल से मुक्त:** न जंग लगे, न ऑक्सीडाइज़ेशन का डर, न रंग लगाने की ज़रूरत.
- **100% टरमाइट प्रूफ:** हर तरह के कीड़ों जैसे सफ़ेद दीमक और मकौड़ियों आदि से खराब नहीं होते.
- **कंसील्ड स्टील की अधिक मज़बूती:** बड़े आकार की खिड़की-दरवाज़ों के लिए अतिरिक्त शक्ति
- **सही-सटीक सिधाई (अलाइनमेंट):** पूरी अनुरूपता के साथ कंप्यूटर-नियंत्रित मशीनों द्वारा वेल्ड किए गए.
- **पूर्णतया सीलबंद:** धूल-कचरे से संपूर्ण सुरक्षा के लिए ई पी डी एम गास्केट द्वारा सुसज्जित ताकि आपको अतिरिक्त इंस्यूलेशन मिले। उपरांत आवाज़ में भी कमी आये.
- **डबल ग्लेज़िंग:** इस अनोखी विशेषता के कारण आपके कमरे को गर्म या ठंडा रखने के लिए होने वाले बिजली के खर्चे में 30% तक की कमी.
- **अंतर्निर्मित पानी की विशेष निकासी-प्रणाली:** बारिश के पानी को निकाल बाहर करे. यानी ऐसी विशेषता जो इस देश में आपने पहले कभी न देखी न सुनी

इंजिनियरिंग उत्कृष्टता

- **बेहतरीन डिज़ाइन:** अधिकतम स्थिरता और बहुपयोगिता के लिए कंप्युटर द्वारा तैयार की गई डिज़ाइनें.
- **बेहतरीन फ़िटिंग:** उत्तम फ़िटिंग के साथ उपलब्ध सुरक्षा के लिए साथ में अतिरिक्त लोहे की जाली भी उपलब्ध है.

अस्पतालों, कंप्यूटर रूमों, इलेक्ट्रॉनिक प्लांटों, खाद्य फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्युटिकल्स प्लांटों से लेकर हर ऐसी जगह के लिए सर्वोत्तम जहां धूल-रहित वातावरण की आवश्यकता होती है. व्यावसायिक और आवासीय इमारतों के लिए अत्यधिक उपयोगी पेड़ों और जंगलों को काटने से बचाने और ऊर्जा की बचत करने के कारण ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं. इसलिए अब यदि अपने नये भवन-निर्माण या पुरानी इमारत के लिए आपको पी.वी.सी. खिड़की और दरवाज़े की ज़रूरत पड़े तो याद रखिए–सिन्टेक्स का नाम.... जो है सबसे समझदारी का काम!

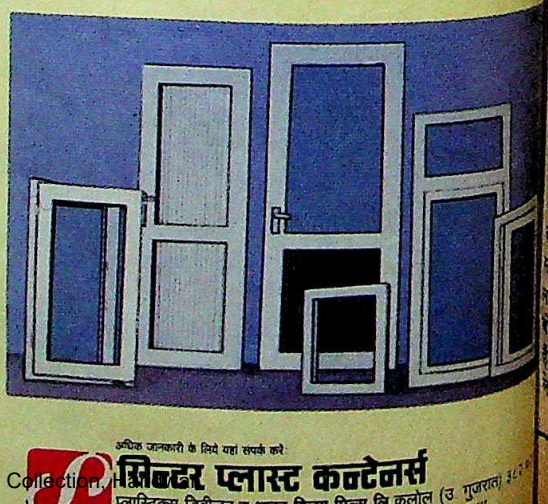

सिन्टेक्स
दुनिया की नं. १ प्लास्टिक पानी की टंकियों के निर्माता की ओर से

अधिक जानकारी के लिये यहां संपर्क करें:
शिवदर प्लास्ट कन्टेनर्स
प्लास्टिक्स डिवीजन द भारत विजय मिल्स लि. कलोल (उ. गुजरात)
फोन:(०२७६४), २२२८, ३१४४, ३१४५ ग्राम: "SINTEX"
टेलेक्स: ०१२०५-२०२ SPC IN फैक्स (०२७६४) २४३६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गोवा

काली घटाओं का बुलावा

'बरसात में सैर' का नारा सफल

सैर-सपाटा, बरसात और गोवा—तीनों का संयोग यों तो विचित्र ही माना जाता मगर इस संयोग ने अच्छा-खासा गुल खिला रखा है गोवा में. पिछले पखवाड़े पणजी के डाबोलिम हवाई अड्डे पर उतरने वाले पर्यटकों की संख्या हजारों में थी. पिछले वर्ष जून से सितंबर के बीच ठीक बरसात के दिनों में 2.02 लाख पर्यटक गोवा पहुंचे थे. 1983 में यह संख्या मात्र 1.15 लाख थी. तब पांच सितारा होटलों ने गोवा को काली घटाओं और मानसूनी फुहारों की रोमांटिक छवि के साथ प्रचारित करना शुरू किया था.

उछलते समुद्र, सुनसान समुद्र तट, लगातार चेतावनी के बोर्ड कि समुद्र में न जाएं, और ऊपर से गड़बड़ यातायात. इतनी असुविधाओं के होते सामान्य सैलानी भला गोवा जाने की जहमत क्यों उठाए. हां, हनीमून के लिए ये सारे संयोग जरूर माकूल बैठते हैं, या फिर किसी महान साहित्यिक रचना के लिए. लेकिन मार्के की बात यह है कि बरसात में गोवा की सैर के लिए आज केवल नवविवाहित जोड़े ही नहीं, दूसरे कई तरह के लोग भी आ रहे हैं.

गोवा के पर्यटन विभाग की पहल पर होटलवालों ने पिछले वर्ष एक मंच बनाया और 'वेमौसम गोवा की सैर' को प्रचारित किया. 'द रेनड्रॉप्स पैकेज' नामक इस पर्यटन प्रस्ताव को प्रचारित करने का बजट 8 लाख रुपए था. नतीजतन होटलों में ठहरने वालों की संख्या 16 फीसदी बढ़ गई.

पुणे के व्यापारी अरविंद कनोरिया कहते हैं, "यह शानदार पैकेज है." 2495 रुपए में एक दंपती गोवा के किसी बड़े होटल—ताज होलीडे विलेज, फोर्ट अगुआडा बीच रिसॉर्ट या ओबेराय बोग्मालो बीच—में तीन रात और चार दिन ठहर सकता है. इसमें खाने और हवाई अड्डे से आने-ले जाने का खर्च शामिल है. ओबेराय अस्पताल के प्रबंधक दिलीप निझावन कहते हैं, "लोग सोचते हैं कि बारिश बुरी चीज है. लेकिन सच तो यह है कि बारिश में गोवा और खूबसूरत लगता है."

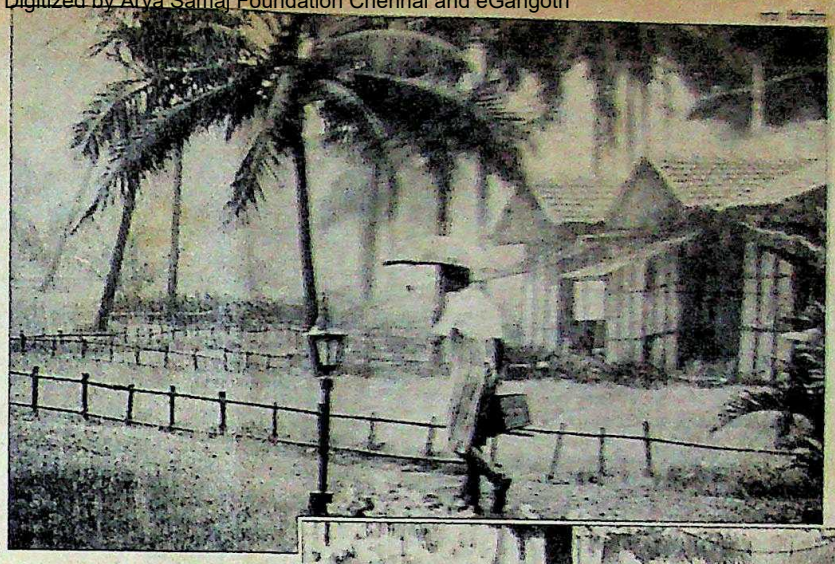

बरसता मौसम, और रेस्तरां में चाय की चुस्कियां: मजेदार अनुभव

अर्थव्यवस्था की मांग के कारण सरकार को पर्यटकों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की अनदेखी करनी पड़ रही है. 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के बाद से इसके ऊपर प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से दो-गुनी यानी 4,492 रुपए बनाए रखने की जिम्मेदारी आ गई है. औद्योगिक आधार कमजोर है, खनन उद्योग की हालत खस्ता है, लोग रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं. ऐसे में गोवा को मजबूरन पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा है. गोवा पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक पी.जी. केंकरे कहते हैं, "पर्यटन हमारे लिए मजबूरी का उद्योग है, पसंद का नहीं." और पर्यटनमंत्री लुई प्रोटो बारबोसा का मानना है कि "गोवा की अर्थव्यवस्था को पर्यटन से पर्याप्त सहारा मिल सकता है."

लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना नहीं. पर्यटन विभाग बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं दिखता. 1991 तक होटलों में 59,000 बिस्तरों की जरूरत होगी लेकिन शायद 33,500 ही उपलब्ध हो पाएंगे. 1988 में पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की 8.27 लाख से बढ़कर 9 लाख होने की उम्मीद है. लेकिन पंजीकृत टैक्सियां मात्र 1757 ही हैं. इंडियन एअरलाइंस की 22 उड़ानें हर हफ्ते दिल्ली, बंबई और बंगलूर से गोवा पहुंचती हैं. मगर होटलवालों के अनुसार यह अपर्याप्त है. और तो और, जुलाई 1987 में जब भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कार्रवाई के लिए जहाजें ले गई तब से बंबई से गोवा की जहाज सेवा बंद है.

फिर भी पर्यटकों का आना जारी है. इसलिए गोवा के योजनाकारों को ऐसे उपाय करने होंगे ताकि पर्यटक सिर्फ नवंबर से मार्च के मौसम में ही न आएं. तभी उपलब्ध साधनों के बूते उनकी आवभगत भी की जा सकेगी और सरकार संसाधन भी जुटा सकेगी. इसी मकसद से 'बरसात में गोवा की सैर' का नारा प्रचारित किया गया है. गोवा पर्यटन विभाग के निदेशक वी.ए.पी. महाजन कहते हैं, "हम बरसात में सैर का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि दूसरे मौसम में पर्यटकों की भीड़ इतनी न हो जाए कि हम उनके लिए समुचित व्यवस्था न कर पाएं." यानी मानसून पर्यटन के लिए भी वरदान सिद्ध हो इसके प्रयास जारी हैं.

—सलिल त्रिपाठी, गोवा में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हॉकी

पुराने दिग्गजों की नींद टूटी

भारत और पाकिस्तान अपनी हॉकी का स्तर सुधारने को प्रयत्नशील

एक जमाना था कि भारत और पाकिस्तान जब कभी हॉकी के मैदान में आमने-सामने उतरते थे तो पूरे उपमहाद्वीप में हॉकी का बुखार चढ़ जाता था. लेकिन एक के बाद एक कई पराजयों के कारण यह बुखार उतरता गया. मगर पिछले पखवाड़े जब ये दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी छह टेस्ट मैचों की शृंखला में भिड़े तो एक बार फिर पुराना माहौल वापस लौटता लगा.

दोनों टीमों में देसी शैली का बढ़िया खेल दिखाने की जैसे होड़ मच गई थी. नैरोबी प्रतियोगिता और पाकिस्तान से कुछ मैच जीतने वाली भारतीय टीम के प्रति भारत में कुछ अधिक ही दिलचस्पी थी. लेकिन इस शृंखला के खत्म होने से पहले ही यह स्पष्ट हो गया कि इन दोनों ही टीमों को ओलंपिक में सेमी फाइनल तक पहुंचने के लिए भी काफी संघर्ष करना होगा.

निराशा का माहौल समाप्त हुआ है. उम्मीद की किरणें दिखने लगी हैं. भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद के इस बयान में भी इस उत्साह की झलक है, "हॉकी से जुड़े अधिकारी टीम के चुनाव पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं देते थे. हमने यह स्पष्ट कर दिया कि जहां तक परिणाम की बात है, हम बहुत ही गंभीर हैं."

विल्सडेन विश्वकप प्रतियोगिता में पराजय के 18 महीने बाद तक भारत का हॉकी जगत जैसे सदमे में डूबा हुआ था. टीम को संवारने की कोई कोशिश नहीं की गई. इस दौरान उसने सिर्फ दिल्ली में हुई इंदिरा गांधी गोल्डकप प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें छह टीमों में उसका स्थान पांचवां था और लखनऊ में हुई प्रतियोगिता में सात टीमों में उसे तीसरा स्थान मिला.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में हिचक का एक कारण तो यह था कि भारतीय हॉकी टीम का सिओल ओलंपिक में शरीक होना तय नहीं था. इस साल मार्च में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर एम.एम. आतिफ द्वारा भारत के पक्ष में की गई जोरदार वकालत के बाद ही भारत का सिओल में खेलना पक्का हो पाया. और फिर एकाएक सरकार और भारतीय हॉकी संघ ने टीम को दुरुस्त करने का फैसला किया. भारतीय टीम के मुख्य प्रशिक्षक एम.पी. गणेश स्वीकार करते हैं, "हमारे यहां गंभीर दीर्घकालिक योजना नहीं बनती. हमें टीम तैयार करने के लिए छह महीने से भी कम का जो समय दिया गया उसमें हम टीम को तालमेल के साथ खेलने भर का प्रशिक्षण ही दे पाए हैं."

हमारे पास अनुभव के नाम पर दो ओलंपिक खेल चुके मौजूदा कप्तान एम.एम. सोमैया, मर्विन फर्नांडीस और मोहम्मद शाहिद ही हैं. सोमैया और मर्विन पर तो 1985 में ढाका में हुई वारदात के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेलने पर रोक लगा दी गई थी. गणेश और दूसरे प्रशिक्षक बी.पी. गोविंदा ने खिलाड़ियों की 5-3-2-1 की परंपरागत संरचना को ही चलाने का फैसला किया है. गणेश ने कहा, "वे लोग गेंद पर नियंत्रण रखने और लगातार हमला बनाए रखने के लिए अधिक नपे-तुले पास देने में कामयाब हो रहे हैं."

निरंतर दबाए रखने वाली बात शुरू में दिल्ली और लखनऊ के टेस्टों में तो देखने को मिली पर ग्वालियर में हुए तीसरे टेस्ट में नहीं. पाकिस्तान के पुराने नामी खिलाड़ी समीउल्लाह ने कहा, "दोनों टीमों के खेल में अभी काफी बेहतरी की गुंजाइश है."

दोनों टीमों में शायद खास फर्क यह था कि

पाकिस्तानी टीम को पिछले दो वर्ष निरंतर प्रशिक्षण मिल रहा है और उसने अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया है. उसने अपने यहां खेलने के लिए बाहर की टीमों को भी बुलाया है.

इस उपमहाद्वीप के बाहर की टीमों के साथ खेलने से भारत को भी ओलंपिक तैयारी में महत्वपूर्ण मदद मिलती. विशेषकर को तेजतर्रार यूरोपीय हॉकी का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में भी मदद मिलती. और हाल में खेल के नियमों में

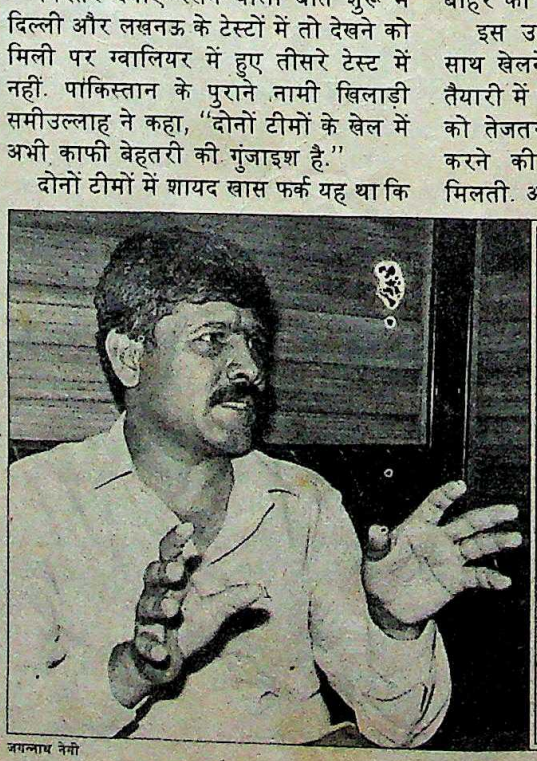

जगन्नाथ नेगी

"हमारे यहां दीर्घकालिक योजना नहीं बनती. टीम तैयार करने के लिए छह महीने से कम समय दिया गया और हम तालमेल से खेलने भर का प्रशिक्षण दे पाए"

एम.पी. गणेश
भारतीय टीम के मुख्य प्रशिक्षक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में भिड़ंत: कमजोरियां उजागर

बदलाव हुए हैं उनसे भी खिलाड़ियों का पाला पड़ेगा होता. यह माना जाता है कि ये परिवर्तन यूरोपीय तरीके से खेलने वालों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे. जैसे पेनाल्टी कार्नर और लांग कार्नर को गोल में बदलने के नियम में काफी बदलाव हुए हैं.

सिंथेटिक मैदान पर खेल बहुत तेज हो जाता है. ऐसे मैदान पर खेलने के लिए खिलाड़ियों के दमखम की भी जरूरत होती है. भारतीय टीम के साथ जाने वाले डॉक्टर बिपिन भल्ला की चेतावनी थी, "बेहतर पैडवाले जूतों के बिना खिलाड़ियों को इस मैदान पर खेलने में बहुत मुश्किल होगी. उनके पैरों पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा." लेकिन मुश्किल यह है कि सिर्फ राष्ट्रीय टीम में आए खिलाड़ियों को ही बढ़िया जूते मिल पाते हैं.

सिंथेटिक मैदान तो 40 से 50 लाख रुपए तक में बनता है लेकिन सस्ते किस्म का ऐसा मैदान 25 लाख रुपए में भी बन सकता है. ब्रिटेन और हॉलैंड ने अपने यहां उन अनेक जगहों पर ये सस्ते मैदान बनाए जहां से खिलाड़ी राष्ट्रीय टीमों में आते हैं. भारतीय टीम के मैनेजर हमनलाल शर्मा कहते हैं, "आपने यहां क्लब स्तर की प्रतियोगिताएं तो समाप्त ही हो गई हैं और कई राज्यों में राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं की कौन कहे, जिलों में ही संगठन नहीं है. इसे भारत का राष्ट्रीय खेल कहना अपमानजनक मजाक ही लगता है." भारतीय हॉकी संघ ने भी इस खेल को बढ़ाने और लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ नहीं किया है. शर्मा कहते हैं, "12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों की अलग-अलग प्रतियोगिताएं जरूर होनी चाहिए. ऐसा होने से ही हम प्रतिभाओं का खजाना जुटा पाएंगे." लेकिन नामी फुल बैक रहे इंका सांसद असलम शेर खां का कहना है, "बहुत सीधी-सी बात है जब उद्योग बीमार होते हैं तो सरकार उनकी स्थिति का जायजा लेती है और सुधार के लक्षण न दिखने पर उन्हें बंद कर देती है. मेरा तो मानना है कि देश में खेल के बीमार उद्योगों को भी बंद कर देना चाहिए."

टीम को मजबूत बनाने के उपायों के तहत विशेषज्ञों द्वारा तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना और दौरों के दौरान टीम के साथ डॉक्टर और एक खेल मनोवैज्ञानिक भेजना तय किया गया है. कप्तान सोमैया ने कहा, "ओलंपिक के लिए तैयारी में हमें इससे मदद मिली है." लेकिन सिओल में स्वर्णपदक का दावेदार बनने के लिए इतना ही कुछ जरूरी नहीं है. गणेश कहते हैं, "अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम वहां कोई-न-कोई पदक पाने की उम्मीद रखते हैं."

दीर्घकालिक योजना खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने तथा अधिक प्रतियोगिताओं के लिए और सिंथेटिक मैदान बिछाने के लिए काफी पैसा चाहिए. भारतीय हॉकी संघ इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जितना अमीर नहीं है. प्रसाद कहते हैं, "समस्या पैसे की है. अभी तक व्यावसायिक घरानों ने हॉकी को प्रोत्साहित करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है."

यह महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि आज खेल की दुनिया में व्यावसायिकता ही श्रेष्ठता की कुंजी है. इस उपमहाद्वीप की हॉकी में इसी व्यावसायिक नजरिये की कमी है. भारत और पाकिस्तान में प्रतिभाशाली और योग्य खिलाड़ियों की कमी नहीं है. लेकिन इसके साथ व्यावसायिकता और आधुनिक प्रशिक्षण को भी जोड़ना होगा. जब तक ऐसा नहीं होगा हॉकी के ये पुराने दिग्गज नवागंतुकों से पिछड़ते ही जाएंगे.

—अमरनाथ के. मेनन और ब्यूरो रिपोर्ट

"जब उद्योग बीमार होते हैं तो सरकार सुधार के लक्षण न दिखने पर उन्हें बंद कर देती है. देश में खेल के बीमार उद्योगों को भी बंद कर देना चाहिए"

असलम शेर खां
सांसद और पूर्व खिलाड़ी

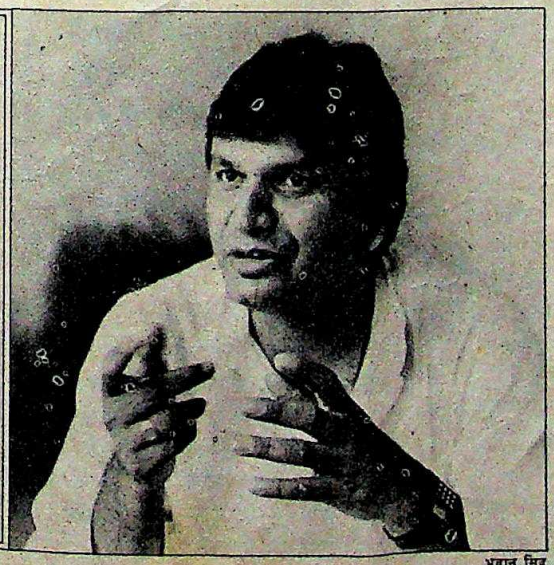

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के. भाग्यराज

भविष्य उज्ज्वल

फिल्मों से पत्रकारिता में

फिल्मी हस्ती के. भाग्यराज कई विधाओं में माहिर हैं. वे एक सफल अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और गीतकार तो हैं ही, अपनी नई फिल्म 'इदुनम्मा आलु' (यह मेरा आदमी है) के साथ वे संगीत निर्देशक भी बन गए हैं. लेकिन अपनी दर्जन भर जुबली फिल्मों के बीच हाल में भाग्यराज ने अपने लिए एक नई भूमिका चुनी है. आठ हफ्ते पहले भाग्यराज ने 'भाग्य' नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की. शुरू में लोग इसे मनबहलाव के लिए खरीदते थे लेकिन धीरे-धीरे इसकी जड़ें जमती गईं और आज इसकी प्रसार संख्या 35,000 पार कर चुकी है. इतना ही नहीं, हर अंक के साथ इसकी प्रसार संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है.

के. भाग्यराज (नीचे); और उनकी पत्रिका 'भाग्य'

भाग्यराज के हाथ में कोई चीज पड़ते ही संवर जाती है. 'भाग्य' पत्रिका इसका सबूत है. इसी पत्रिका के साथ उन्होंने एक और दिशा की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है— वह है राजनीति. वे कहते हैं, "राजनीति में शामिल होने के बारे में अभी कोई बयान देना बहुत जल्दबाजी और असामयिक होगा. हो सकता है, चुनाव अभियान के दौरान मैं किसी राजनैतिक दल से जुड़ जाऊं. भविष्य के बारे में कौन जानता है."

हालांकि भाग्यराज अन्नाद्रमुक के जानकी गुट से सहानुभूति रखने वाले माने जाते हैं लेकिन 'भाग्य' के पहले अंक में द्रमुक नेता एम. करुणानिधि का इंटरव्यू प्रमुखता से छापा गया. पत्रिका के बाद के अंकों में भाग्यराज ने जो सारगर्भित राजनैतिक टिप्पणियां कीं, उनसे कई लोग ताज्जुब करने लगे कि आखिर उनकी वफादारी है किस तरफ. भाग्यराज स्पष्टीकरण देते हैं, "मेरी राजनैतिक टिप्पणियों को किसी के समर्थन या विरोध के रूप में क्यों देखा जाता है. सचाई तो इसके बीच में ही कहीं है." वे कहते हैं, "लोगों को यह बताने की कोशिश में कि राजनैतिक दल नहीं वरन राजनैतिक उम्मीदवार महत्वपूर्ण होते हैं. मैं पत्रिका के माध्यम से अपने विचार फैला रहा हूं." हालांकि दिवंगत एम.जी. रामचंद्रन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लेकिन साथ ही रामचंद्रन ने जयललिता को भी आगे बढ़ाया. जैसा कि भाग्यराज खुद कहते हैं, "एमजीआर ने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जयललिता को भी आगे बढ़ाया और चूंकि इस घटना के बाद जल्दी ही एमजीआर की मृत्यु हो गई, सो यह भ्रम जस का तस है." इससे स्पष्ट है कि भाग्यराज भविष्य में पार्टी पद के लिए अभी से कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इस नाजुक स्थिति में उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं.

भाग्यराज हर चीज संवार देते हैं. 'भाग्य' पत्रिका इसका सबूत है. इसी के साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा है

पौने दो रुपए कीमत वाली इस पत्रिका की अखबार उद्योग के विभिन्न दिग्गजों ने भी सराहना की है. भाग्यराज को फिल्मों में मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा कहते हैं, "मैं यह तो जानता था कि भाग्यराज प्रतिभाशाली हैं लेकिन इस पत्रिका के प्रकाशन से उन्होंने मुझे भी चकित कर दिया." दक्षिण की सबसे बड़ी फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक एवीएम बैनर के बालासुब्रमण्यम भी इससे सहमत हैं, "भाग्यराज ने मासिक की बनिस्बत साप्ताहिक पत्रिका शुरू करके बड़ा साहस दिखाया है. पत्रिका निकालने में जब तक वे नियमित रूप से खुद रुचि लेते रहेंगे, पत्रिका अच्छी तरह से चलती रहेगी."

पत्रिका में राजनैतिक विषय, कहानी, वैज्ञानिक कहानी, फिल्मी खबरें— सब कुछ रहता है. संपादकीय खुद भाग्यराज लिखते हैं. इसके अलावा उनकी एक कहानी की शृंखला भी चल रही है. सवाल-जवाब का एक पृष्ठ भी उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है. भाग्यराज खुद मानते हैं, "अपनी फिल्मों में मैं लोगों से साल में केवल एक बार मिल पाता था— फिल्म के प्रदर्शन के वक्त. लेकिन अब मैं उनसे नियमित रूप से मिलता हूं." पत्रिका की स्थायी प्रतियोगिताएं भी बेहद लोकप्रिय हैं. इसमें सबसे बढ़िया प्रेम-पत्रों की प्रतियोगिता भी शामिल है.

प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका 'जूनियर विकतन' के संयुक्त संपादक माधन कहते हैं, "एक फिल्म निर्माता का पत्रकारिता में आना बहुत असामान्य नहीं है. पहले भी ऐसा हुआ है. हमारा मुख्य प्रकाशन एस.एस. वासन ने शुरू किया था. फिर चो रामास्वामी भी 'तुगलक' पत्रिका निकालकर सफल रहे. करुणानिधि की साहित्यिक प्रतिभा को सब लोग जानते ही हैं. भाग्यराज भी पटकथा लेखक रहे हैं. वे प्रतिभाशाली भी हैं. इसलिए उनकी सफलता पर मैं चकित नहीं हूं." वरिष्ठ लेखक मालन कहते हैं, "भाग्यराज की पत्रिका के पहले कुछ अंक देखकर लगा है कि यह सफल होगी. इसमें एक विशेष धारा दिखी. युवा लेखकों को प्रोत्साहित किया गया. लेकिन यह सब अतीत की बात हो चुकी है. पत्रिका भाग्यराज के विशिष्ट सांचे में ढल गई है."

पत्रकारिता में आए फिल्मी पटकथा लेखकों के पिछले रिकार्ड को देखते हुए भाग्यराज की इस पत्रिका का भविष्य उज्ज्वल दिखता है. यदि भाग्यराज खुद इसकी देखरेख करते रहेंगे और 'पत्रकार बनने की अपनी बचपन से संजोई महत्वाकांक्षा' के अनुरूप अपने को सही-सही ढाल लेंगे तो भविष्य में राजनीति के मैदान में भी शायद 'भाग्य' उनके लिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की मानिंद दिन-ब-दिन निखरता चला जाएगा.

—ललिता वित्तिल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'उल्टा-पुल्टा'

सीधी बात टेढ़े तरीके से

भट्टी की व्यंग्य क्षणिकाओं में संदेश की तल्खी चुभती नहीं

चिड़ियाघर का एक दृश्य. एक परिवार कटघरे में बंद कुछ मनुष्यों को बड़ी हैरत से देख रहा है. गाइड उन्हें बताता है, "ये ईमानदार लोग हैं. 25 साल पहले तक ये दफ्तरों में पाए जाते थे. पर अब यह नस्ल लुप्तप्राय हो चुकी है. ऐसे लोग थे जो विरले ही, अपनी तनख्वाह में ही गुजारा कर लिया करते थे." कैमरा बच्चों की तरफ घूमता है. "हा-आ-आ! क्या कमाल लोग थे." पर पिता नफरत से सिर झटकते हुए बोलते हैं, "अरे! बहुत पिछड़े हुए थे." अगला दृश्य: स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापनों सरीखा, डॉक्टर की वेशभूषा में एक आदमी दर्शकों से कहता है, "अपने बच्चे को शुरू से ही घूसखोरी का टीका लगवा लें. वरना उसे ईमानदारी की बीमारी लग सकती है और उसका विकास भी असामान्य हो सकता है. अगर आपका बच्चा एक साल का हो गया हो तो उसे आज ही यह टीका लगवाना न भूलें. ये टीके सभी अस्पतालों में मिलते हैं."

दूरदर्शन के इस सबसे जोरदार दृश्य को प्रस्तुत करने वाले शख्स हैं—जसपाल भट्टी. टीवी पर 'उल्टा-पुल्टा' की कड़ियों में उनके छोटे-छोटे व्यंग्य प्रहसन बहुत ही लोकप्रिय हैं जो लोगों को हंसा-हंसाकर लोट-पोट कर देते हैं. यहां पर हंसी पैनी तलवार का काम करती है क्योंकि यही भारतीय समाज के पट खोलकर उसकी सचाइयों के दर्शन करा देते हैं.

चंडीगढ़ के निवासी और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर काम कर रहे भट्टी भारतीय समाज के अंधेरे कोनों में रोशनी डालकर हंसी-हंसी में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं. भट्टी की कामयाबी का राज है उनकी मधुर आवाज और बड़ी सफाई से अपनी बात का प्रस्तुतिकरण. औपचारिक और फूहड़ हास्य पेश करने वाले दूरदर्शन के परदे पर भट्टी के प्रहसन एक सुहाने बदलाव की तरह हैं.

भ्रष्टाचार उनका प्रिय विषय है. होंठों पर जरा भी मुस्कान लाए बगैर भट्टी कहते हैं, "राष्ट्रीय कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को ही लक्ष्य बनाया जा सकता है. राष्ट्रीय नेटवर्क में ऐसी चीज दिखाई जानी चाहिए जिसमें हर इलाके की दिलचस्पी हो. कुछ विषय एक तरह के इलाकों के लिए प्रासंगिक हैं तो कुछ दूसरे इलाकों के लिए. पर भ्रष्टाचार का मुद्दा सर्वव्यापी है."

कार्टून: अजीत नैनन

भट्टी के ऐसे विशेष प्रहसनों का भी एक मजेदार इतिहास है. वे अपने एकमात्र गुरु आर.के. लक्ष्मण से काफी प्रभावित हैं. इसी के चलते 'द ट्रिब्यून' से उनका संबंध जुड़ा जिसमें आज भी 'ऑडली स्पीकिंग' नामक स्तंभ में उनके कार्टून छपते हैं. जब भट्टी को लगा कि वे दूसरे लक्ष्मण नहीं हो सकते तो उन्होंने छोटे परदे की ओर रुख किया. 'रंग विच भंग' नाम से उनके पंजाबी प्रहसन सबसे पहले जालंधर दूरदर्शन से प्रसारित हुए. ये खूब चर्चित हुए और एक बुजुर्ग औरत की हंसते-हंसते मौत भी हो गई थी. दूरदर्शन भी प्रहसनों से काफी प्रभावित हुआ. दूरदर्शन के मौजूदा उप-महानिदेशक अलबेल सिंह ग्रेवाल ने उनसे सुबह के प्रसारण के लिए ऐसा ही कोई हिंदी कार्यक्रम तैयार करने को कहा.

कुछ समय के लिए 'उल्टा-पुल्टा' बीच में बंद भी रहा पर भट्टी जल्द ही उसका स्वरूप बदलेंगे जिसमें एक-एक विषय पर नई क्षणिकाएं होंगी. इस बीच 'उल्टा-पुल्टा' को सुबह के बजाय दो कार्यक्रमों के बीच के समय में पेश किया जाने लगा है.

परदे के अलावा भट्टी की गतिविधियों में नॉनसेंस क्लब भी शामिल है जिसे कुछ साल पहले उन्होंने चंडीगढ़ में स्थापित किया. यह नॉनसेंस क्लब ही 'उल्टा-पुल्टा' का जनक है. यह क्लब हठी राजनीतिकों और नौकरशाहों को कोंचने के लिए व्यंग्य का इस्तेमाल करता है. लापरवाही की वजह से जब चंडीगढ़ की झील सूख गई तो क्लब के सदस्यों ने उस पर स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर डाली. वहां उन्होंने यहां तक लिख दिया, "कृपया यहां आत्महत्या की कोशिश न करें. पानी जरूरत के मुताबिक गहरा नहीं है."

पिछले आम चुनाव में उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने, पूर्ण असुरक्षा निश्चित करने और नियम-कानून का नामोनिशां मिटा देने की गारंटी देता था. पर मतदान के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने इस उम्मीदवार का नाम 'वापस' ले लिया क्योंकि वह बाकी उम्मीदवारों का मुकाबला नहीं कर सकता था.

अपनी कामयाबी का राज बताते हुए भट्टी कहते हैं, "मैं उलटी तरह से अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं. मसलन अगर किसी छोटे बच्चे से कहें कि मिट्टी मत खाओ तो सबसे पहले वह बाहर जाकर मिट्टी ही खाएगा. पर अगर उसे कहा जाए कि चम्मच-प्लेट लेकर बाहर जाओ और मिट्टी खाओ तो वह शायद हिचके. इस तरह लोग कुछ सोचने को मजबूर होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें भ्रष्ट होने से रोक सकता हूं."

यह बहुत बढ़िया संदेशपूर्ण मनोरंजन है जिसमें संदेश की तल्खी भी महसूस नहीं होती और उनकी हास्य झलकियां मन को गुदगुदाती रहती है.

—मधु जैन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रामायण

मांग पर होगी वापसी

छोटे परदे के बढ़ते सम्मोहन का फायदा सत्ता दल को

करीब तीन महीने तक वनवास भोगने के बाद 'भगवान' राम इस साल दशहरे पर फिर छोटे परदे पर लौटेंगे. लेकिन उनकी इस वापसी के पीछे जबरदस्त जनभावना और सोचे-विचारे राजनैतिक गणित की एक लंबी कहानी है.

कुछ ही महीने पहले दूरदर्शन ने 'रामायण' सीरियल की एक और मियाद बढ़ाने के लिए साफ 'ना' कर दी थी. उसे 26 अतिरिक्त किस्तों की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी. निर्माता रामानंद सागर ने तो लिखकर भी दे दिया था कि वे और अधिक विस्तार के लिए नहीं कहेंगे.

लेकिन पिछले पखवाड़े अचानक सब कुछ बदल गया. केंद्रीय सूचना और प्रसारणमंत्री हरकिशनलाल भगत ने संसद में घोषणा की कि लोगों की मांग पर सरकार 'रामायण' को जारी न रखने के फैसले पर फिर से विचार करेगी. इस अचानक बदले हुए रवैये के बारे में पूछे जाने पर भगत ने 'इंडिया टुडे' को बताया, "यह एकदम सहज प्रतिक्रिया ही थी. रामायण को जारी रखने के लिए सभी समुदायों और धर्मों के लोगों ने अनुरोध किया है."

जाहिर है इस सहजता के पीछे खालिस राजनैतिक मजबूरियां हैं. 22 जुलाई को जालंधर के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी. कुछ ही दिनों बाद अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के उपाध्यक्ष करमचंद परदेसी ने रामायण के मूल लेखक महर्षि वाल्मीकि की भूमिका दिखाए बिना ही सीरियल बंद कर देने पर सागर और दूरदर्शन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. अनुसूचित जाति कल्याण संघ और अखिल भारतीय समता सैनिक संघ ने केंद्र को चेतावनी दी कि वाल्मीकि की भूमिका न दिखाए जाने पर उनके समुदाय में रोष बढ़ता जा रहा है.

जालंधर में तो 25 जुलाई को लाठी-चार्ज भी हुआ जिसमें 35 सफाई कर्मचारी घायल हो गए. इसके तुरंत बाद अनुसूचित जाति के लगभग 40 सांसदों ने राजीव गांधी को रामायण बंद करने के नतीजों के बारे में आगाह कर दिया. 27 जुलाई तक जालंधर और लुधियाना में लगभग 2,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. इससे आंदोलन के पूरे पंजाब (यहां सबसे ज्यादा वाल्मीकि हैं) और पड़ोसी राज्यों में फैल जाने का खतरा पैदा हो गया.

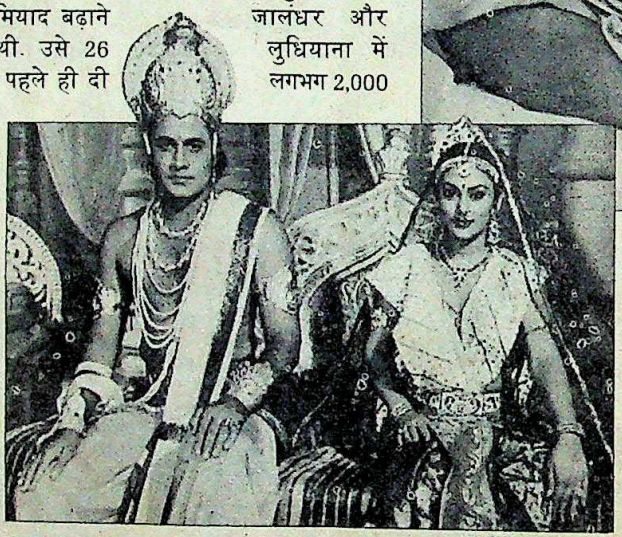

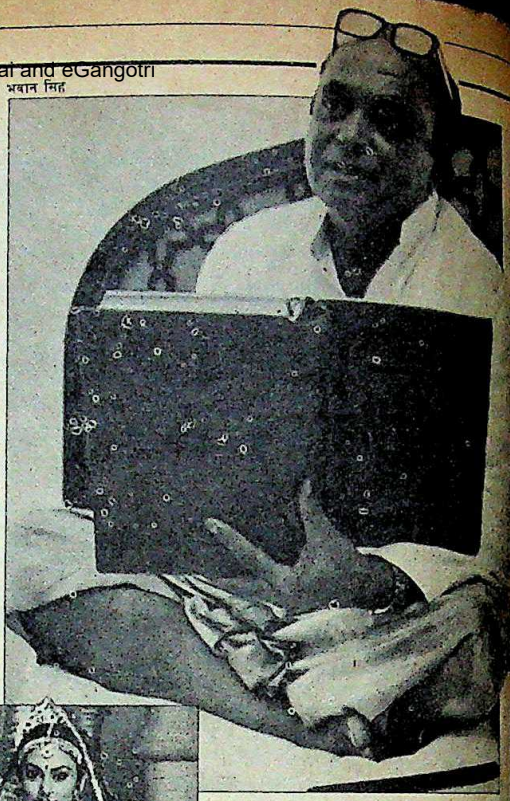

भवान सिंह

वाल्मीकि रामायण के साथ सागर (ऊपर); और 'राम-सीता'

इससे साउथ ब्लॉक और शास्त्री भवन में चिंता फैल गई क्योंकि सत्तारूढ़ दल अनुसूचित जातियों को अपने से अलग-थलग करने का खतरा मोल नहीं ले सकता. हिंदुओं में एक-चौथाई वोट अनुसूचित जातियों के ही हैं. सीरियल की अभूतपूर्व लोकप्रियता को देखते हुए लोगों के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को चोट पहुंचने की आशंका सही भी थी. दूरदर्शन को 23 करोड़ रु. का मुनाफा देने वाले इस महाकाव्य के शुरू होते ही लोग बड़ी श्रद्धा से अपने-अपने टीवी के सामने बैठ जाते थे और बदले में सारा श्रेय सत्तारूढ़ दल को मिलने की उम्मीद भी लगाई गई.

उन्होंने इस महाकाव्य को पूरा क्यों नहीं दिखाया और इसमें सीता वनवास तथा लव-कुश को पालने-पोसने में वाल्मीकि की भूमिका शामिल क्यों नहीं की? यह पूछे जाने पर सागर ने कहा, "मेरे पास वक्त नहीं था. मुझे 78 किस्तों के लिए ही कहा गया था. शुरू में तो 52 किस्तें ही थीं. और फिर इस करार पर दस्तखत भी करवा लिए गए कि मैं इसकी मियाद बढ़ाने के लिए नहीं कहूंगा."

पर बड़े अफसरों में दूसरी ही चिंता दिखती है. वह यह कि लोक लुभावन नारों आदि के प्रति बढ़ते रुझान और सरकार द्वारा भी उसे हवा देना खतरनाक हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि दूरदर्शन से कैसे कामों की उम्मीद की जाती है? लोकप्रियता ही बड़ा पैमाना मानें तो पी.सी. जोशी समिति के जांच नतीजे और सभी घोषित सामाजिक उद्देश्य बेमतलब हो जाते हैं.

रामायण की लोकप्रियता से खुश सागर कहते हैं, "अन्यथा पूरे देश में आग की लपटें फैल जातीं. आपको मालूम है कि दार्जिलिंग में गोरखा मोर्चा और गृहमंत्री की बैठक 'रामायण' के खत्म होने तक स्थगित कर दी गई थी? यहां तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी देर से शुरू हुआ." रामानंद आख्यान ने एक बात तो साबित कर ही दी है कि सत्ताधारियों में टीवी की सम्मोहन शक्ति के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है.

—मधु जैन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुनर्जागरण का अगुआ

द बदरहुड इन सैफ्रन
वाल्टर के. एंडरसन और श्रीधर दामले
प्रकाशक—सेज
कीमत: 150 रु., कुल पृष्ठ: 317

भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में खास तौर से जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के विचारों से अपनी अवधारणा बनाई है. इस अवधारणा के मुताबिक संघ एक सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट संगठन है जो भारत को पीछे की ओर ले जाना चाहता है.

इसकी मान्यताओं के बारे में किसी का चाहे जो विचार हो, राजनैतिक दृष्टिकोण से इसे इतना महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी गहन और विश्लेषक अनदेखी नहीं कर सकते. लेकिन ताज्जुब है कि क्रांतिकारी हिंदू राष्ट्रवादी के पर्याय इस संगठन पर अध्ययन के काबिल नहीं के बराबर लिखा गया.

यह कमी एंडरसन और दामले ने अब पूरी कर दी है. संघ के जन्म की एक प्रमुख वजह है हिंदू पुनर्जागरणवाद का बढ़ता प्रभाव क्योंकि यह संगठन उन आत्मविस्मृत लोगों को नैतिक आधार देने पर जोर देता है जो तेजी से बदलते समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं. इससे जुड़ी यह अवधारणा भी है कि अनुशासित उग्रता में ही हिंदुत्व के पुनरुद्धार की कुंजी है.

संघ का नजरिया इस अर्थ में पिछड़ा हुआ नहीं है कि वह हिंदू समाज को विभाजित रखने वाले धर्म के पहलुओं को जड़ीभूत करने का इच्छुक है. लेकिन खासकर महाराष्ट्र में संघ अभी भी अपनी ब्राह्मण उत्पत्ति का नतीजा भुगत रहा है.

लेखकों ने साफ लिखा है कि संघ राजनीति और राजनैतिक अधिकारों के प्रति अपने संबंधों को लेकर दुविधा का शिकार है. हालांकि यह अपने को सांस्कृतिक संगठन की श्रेणी में रखता है, लेकिन इसके पुराने जनसंघ और मौजूदा भाजपा से सहजीवी और गर्भनाल के रिश्ते हैं.

सत्ता को उकसाने में संघ की उत्सुकता न होने के बावजूद इस पर समय-समय पर प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन यह दुबारा दुगुने जोश से खडा हुआ है. बहुत कम लोगों को पता है कि आजादी के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस संघ के साथ संबंध बनाने के लिए बातचीत चला रही थी. इस बात को भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि चीन के साथ लड़ाई में भारत के मात खा जाने के बाद संघ ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था. दोहरी सदस्यता के मामले की याद अभी भी ताजा है जिसके कारण जनता सरकार का पतन हुआ था.

संघ के कार्यकर्ता: अनुशासित उग्रता

लेखकों ने संघ के भविष्य के बारे में ज्यादा समय और स्थान दिया लेकिन इस संगठन की उलझनों का भी बढ़िया विवेचन किया है. यह भी कि सरसंघचालक (प्रमुख) इस संगठन की सक्रिय भूमिका के बारे में किस हद तक फैसला करते हैं. मसलन मौजूदा सरसंघचालक बालासाहेब देवरस का झुकाव सक्रियतावाद की तरफ है.

यदि संघ की कोई उलझन रही है तो वह राष्ट्र की स्थिति के कारण और बढ़ी है. संघ की शक्ति स्वयंसेवकों में अपनी पूर्ण मूल्य प्रणाली के प्रति संदेहरहित वफादारी के बीज बो देने की क्षमता में निहित है. अब सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के सामने आने से जिसमें क्षेत्रीय उपराष्ट्रीयतावाद और चुनावी राजनीति आग में घी जैसा काम कर रही हैं, संघ का एक बार फिर राजनैतिक व्यवस्था के ताने-बाने में स्वागत हो रहा है. लेकिन हिंदुत्व के पुनर्जागरण के संघ के आदर्श और एक राजनैतिक पार्टी के जरिये घटनाओं को प्रभावित करने के उसके लोभ के बीच का द्विभाजन हमेशा विद्यमान रहता है. इसके लिए बालासाहेब देवरस के हाल के बयानों को ही देख लेना काफी है—खासकर वह बयान जिसमें कहा गया था कि मौजूदा परिस्थितियों में केंद्र में कांग्रेस (इ) का कोई विकल्प नहीं है. इन बयानों पर हुई प्रतिक्रियाओं से नई स्थिति का पता चलता है.

संघ की मूल उलझन यह है कि यह अपने को सदियों के विदेशी शासन के बाद हिंदुत्व के पुनर्जागरण के एक नैतिक बल के रूप में मानता है. जनसंघ और भाजपा के साथ इसके संबंधों ने हमेशा ही समस्याएं खड़ी की हैं क्योंकि पक्षपाती राजनैतिक लड़ाइयों में हिस्सा लेने से उस नैतिक संदेश पर असर पड़ता है जिसे कि यह संगठन फैलाना चाहता है.

राजनीतिक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों के दायरे के बाहर संघ ही एकमात्र संगठन है जिसके पास संगठित कार्यकर्ता हैं. लेकिन असली सवाल यह है कि संघ का मौजूदा नेतृत्व इसकी सक्रियता को कब तक बनाए रख सकेगा.

—एस. निहाल सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाज विज्ञान

बदली प्रवृत्तियों का ब्यौरा

नई पीढ़ी का पश्चिमी सभ्यता से मोहभंग और स्वदेशी प्रेम

पुनः भारतीयता की ओर
समाज विज्ञान
आशारानी व्होरा
प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
पृष्ठः 208; कीमतः 60 रु.

हजारों साल के विदेशी शासन ने भारतीय संस्कृति की गरिमा को धूमिल भले ही कर दिया हो, वह इसे जन-मानस से मिटा नहीं पाया. लेकिन इस सदी के आरंभ में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार और अंग्रेजी भाषा के प्रचलन से ऐसा वर्ग जरूर पैदा हो गया था, जो विदेशी सभ्यता का अंध प्रशंसक और हर देसी चीज को हिकारत से देखने लगा था. पाश्चात्य संस्कृति चूंकि शासक वर्ग की देन थी, इसलिए उससे जुड़े रहना भी प्रतिष्ठा का प्रतीक था. महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन और स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद जैसे मनीषियों के भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाने के प्रयासों के बावजूद विदेशी सभ्यता का मोहभंग नहीं हुआ. लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दो दशकों के सांस्कृतिक ठहराव के बाद—यानी स्वतंत्रता के बाद जन्मी पीढ़ी ने युवा होने पर भारतीय संस्कृति की गरिमा को फिर से पहचाना है. आंशिक रूप से ही सही, उसे पश्चिमी सभ्यता के मुकाबले बेहतर मानकर उस पर गर्व करना सीखा है. यही कथ्य है आशारानी व्होरा की इस पुस्तक का, जिसमें नई पीढ़ी के स्वदेशी प्रेम की दो खंडों—'जीवन शैली' और 'संस्कृति चिंतन' में व्याख्या की गई है. लेखिका का मानना है कि यह पश्चिमी सभ्यता की ऊपरी चकाचौंध से मोहभंग होने पर पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटने की शुरुआत है. 'जीवन शैली' खंड में बताया गया है कि किस प्रकार नई पीढ़ी आधुनिक परिवेश में पलकर भी पुरानी परंपराओं से जुड़े रहना चाहती है. हर स्वदेशी चीज की सोंधी महक उसे अपनी ओर खींचती है. पूर्व और पश्चिम के द्वंद्व में फंसी पुरानी पीढ़ी के मुकाबले नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति की ही पक्षधर है. मामला चाहे शादी-ब्याह का हो, वेशभूषा का, व्रत-उपवास का, सौंदर्य प्रसाधनों का या घर की सजावट का. इस खंड में लेखिका ने अपनी बात प्रसंगों के जरिये पात्रों से कहलवाई है. पहले खंड के दो अध्याय 'अच्छे लगते हैं रस्मोरिवाज' और 'भक्ति संगीत और संकीर्तन से शांति की खोज' उल्लेखनीय हैं. पहले अध्याय में एक आधुनिक मां को विदेश में शिक्षित बेटी के परंपरागत रीति से ब्याह करने की बात अखरती है. शादी के बाद भी वह उसे ससुराल वालों पर अपना रौब जमाने के लिए अंग्रेजी बोलने, अमेरिकी जीवन शैली अपनाने की ही सलाह देती है पर बेटी भारतीय संस्कृति और जीवन शैली को ही श्रेष्ठ बताकर उसे निरुत्तर कर देती है. इसी तरह मां को बेटी का विदेश से डिग्री लेने के बावजूद गृहिणी और मां बने रहने पर ही संतुष्ट रहना नहीं सुहाता. दूसरे अध्याय में नई पीढ़ी के बढ़ते धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव को दिखलाया गया है. जैसे भजनों के कैसेटों की बढ़ती बिक्री, पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा कीर्तन-सभाओं का आयोजन और भारतीय ही नहीं बल्कि भौतिकता से ऊबे विदेशियों द्वारा भी मानसिक शांति के लिए भारतीय अध्यात्म का सहारा लेना. इस खंड के बारहों अध्यायों के प्रसंग रोजमर्रा की जिंदगी जुटाए जाने के बावजूद गढ़े गए, अस्वाभाविक, सतही और पूर्वाग्रह से प्रेरित लगते हैं. खंड में गहन चिंतन [illegible] भी अभाव है. नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं [illegible] प्रति क्यों दीवानी हो रही है, इसका [illegible] लेखिका के पास कोई ठोस जवाब नहीं है [illegible] ही इस बात का कि बढ़ते स्वदेशी प्रेम [illegible] बावजूद प्रतिभाओं का विदेशों में पला[illegible] क्यों जारी है. विदेशी चीजों का मोह [illegible] नहीं छूट रहा. बिखरते परिवार [illegible] तलाकों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही [illegible]

दूसरा अध्याय 'संस्कृति चिंतन' अपेक्षाकृत गंभीर और चिंतनशील बन पड़ा है. [illegible] खंड के नौ अध्यायों में भारतीय संस्कृति [illegible] प्रमुख पहलुओं—धर्म, अध्यात्म, योग, दर्शन, तंत्र-विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की प्रामाणिकता और विदेशों में इनकी लोकप्रियता का ब्यौरा है. साथ ही यह भी कि कैसे विदेशी शासन [illegible] अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की परतें जमती चली गईं और यह संस्कृति जादू-टोनों, सपेरों, गरीबी, भीरुता, दासता का पर्याय बनती चली गई. अब धीरे-धीरे परतें उठ रही हैं और संसार हैरान है [illegible] 'प्रकृति के जिन गूढ़ रहस्यों को भारत के मनीषियों ने सभ्यता के आदिकाल में ही [illegible] लिया था पश्चिम के वैज्ञानिक अब [illegible] पाए हैं.' इस खंड के दो अध्याय 'योग और विज्ञान' तथा 'धर्म, अध्यात्म और विज्ञान एक वैश्विक धर्म की खोज में' काफी पठनीय हैं. पहले में योग दर्शन की प्रामाणिकता और निजी जीवन में उसकी सार्थकता पर जोर है तो 'धर्म अध्यात्म और विज्ञान...' में धर्म और अध्यात्म को आज की वैज्ञानिक कसौटी पर [illegible] उतारने का प्रयास है.

> **जब किसी राष्ट्र पर विदेशी भाषा हावी होने लगती है तो राष्ट्र की संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि संस्कृति भाषा पर ही टिकी होती है, वही इसका आधार है**
>
> इसी किताब से

खंड के अंतिम दो अध्याय 'हिंदुत्व की पहचानः देश और उसके बाहर' और 'संस्कृति, [illegible] नीति और राष्ट्रचिंतन' में क्रमशः हिंदू धर्म और संस्कृति की परिभाषा, व्याख्या और देश [illegible] गहराते राजनैतिक-सांस्कृतिक [illegible] का विवेचन है. पहले अध्याय में लेखिका बताती हैं कि इतने वर्षों के विदेशी शासन और सामाजिक कुरीतियों के बावजूद [illegible] और संस्कृति जड़ से मिटी क्यों नहीं [illegible] आज क्यों विदेशियों के लिए [illegible] और आकर्षण का विषय बनी है. [illegible] अध्याय में जीवन के हर क्षेत्र [illegible] राजनीति में मूल्यों की गिरावट का [illegible] है. लेकिन लेखिका आश्वस्त है कि नई [illegible] भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर [illegible] संस्कार और समाज का परिष्कार [illegible]

—विमल [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Radios 2-in-1s Calculators Projectors Digital Watches

KELTRON

RELYTRONICS

No better guarantee

रिलायट्रॉनिक्स.

अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके साथ विश्वसनीयता जुड़ी है.

वैसे हमारे लिए विश्वसनीयता महज एक शब्द ही नहीं बल्कि पिछले बीस सालों में विस्तृत शृंखला के औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों के निर्माण मे हासिल किये गये हमारे अनुभव और तकनीकी कुशलता का प्रतीक है

इन उत्पादनों में टी.वी, रेडियो, टू-इन-वन, कैलकुलेटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के अलावा संचार, देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किये जानेवाले इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम भी शामिल हैं. और तो और, हम इन उत्पादनों में इस्तेमाल होनेवाले कलपुर्जे, जैसे कैपेसिटर्स, डायोड्स, रेसिस्टर्स, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स वगैरह भी बनाते हैं.

यही नहीं, कई नामी कंपनियां भी अपने उत्पादनों के निर्माण के लिए हमारे ये कलपुर्जे खरीदती हैं

केल्ट्रॉन रिलायट्रॉनिक्स : इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वसनीयता के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं.

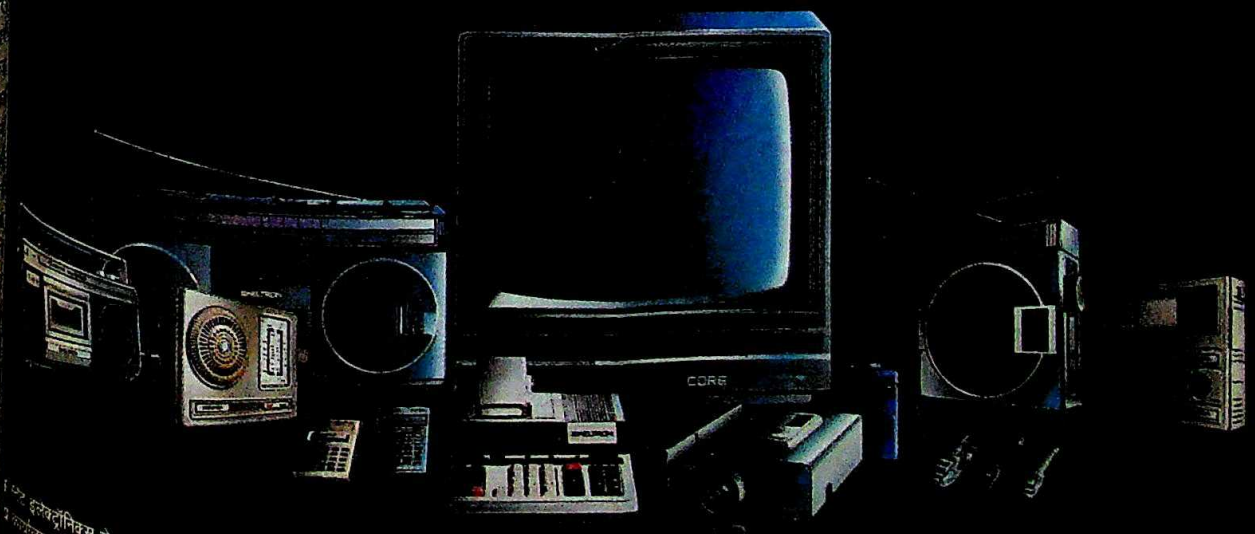

इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ; कॉर्पोरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, (कन्ज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स), शस्थमंगलम, त्रिवेन्द्रम ६९५ ०१० फोन ६९१०६ शाखा व अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, कालीकट, कोचीन, गुवाहाटी, हैदराबाद, मद्रास, मदुराई, नयी दिल्ली, पटना, त्रिवेन्द्रम और विशाखापट्टणम

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाज़ करे सारा परिवार 'अपना घर' ऐसा उपहार

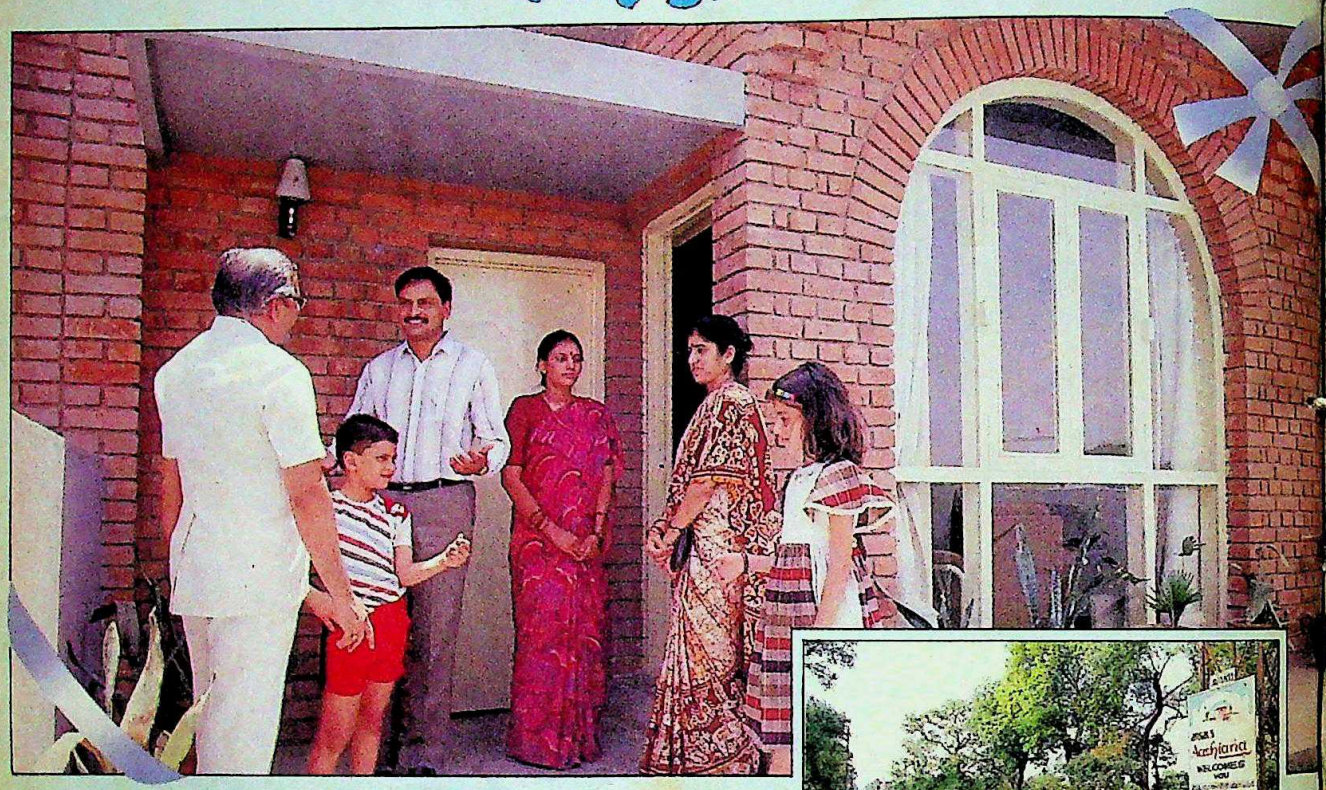

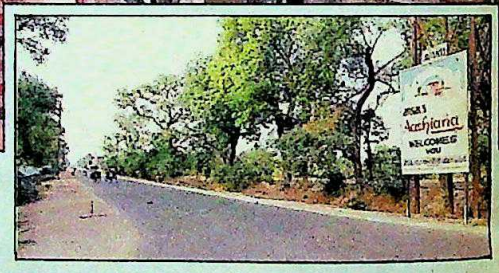

वह घर जिसके साथ है एक ताज़ा, स्वस्थ वातावरण

आशियाना में आपका अपना घर, आपके परिवार के लिए एक ऐसा उपहार जो सबसे अनोखा और आदर्श होगा. यहाँ एक घर का मतलब होगा सम्पूर्ण और सदाबहार जीवन-शैली, क्यूंकि घरों के अलावा आशियाना में आपके लिए और भी बहुत कुछ है. पार्कों और उद्यानों की हरियाली में रचा-बसा एक ताज़ा स्वच्छ वातावरण आपके बच्चों के विकास के लिए खुले मैदान और पार्कों की साफ़ हवा, उनकी शिक्षा के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित चिरंजीव भारती स्कूल की शाखा. यहाँ पर सुबह आपका स्वागत करेगी ताज़ा हवा और शाम को गुलमोहर के फूलों की महक.

यही नहीं यहाँ होंगे मनोरंजन के लिए विशेष क्लब; अस्पताल, दैनिक ज़रूरतों की खरीददारी के लिए शॉपिंग सेन्टर- 'खजाना' है न सभी कुछ एक अनूठा अंदाज़! उस जीवन का जो हमेशा से आपके परिवार की चाह है.

और यही है समय, इस चाह को साकार रूप देने का. क्यूंकि आशियाना 1990 में बनकर पूर्ण होने के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है. इसलिए 5 प्रकार के निर्मित घरों और 6 आकारों के प्लॉटों में से अपनी पसन्द चुनिए और निश्चिंत हो जाइये.

विशेषताएं

- प्लॉट प्राप्त करें 1988 में और निर्मित घर 1989 में विभिन्न चरणों में.
- तेजी से विकसित हो रहा है– 10 नमूने के घर तैयार, 300 घरों का निर्माण जारी 25 किमी सेक्टर मार्ग तैयार, बिजली पानी की व्यवस्था का कार्य जारी.
- सुविधा जनक बुकिंग राशि. आसान ब्याज़-मुक्त किस्तों में भुगतान.
- रु. 2.5 लाख तक के आवासीय ऋण उपलब्ध. 15 वर्षों में चुकाइये.
- मल एवं जल निकासी प्रणाली के नक्शे स्वीकृति के लिए प्रेषित

अन्सल आशियाना लखनऊ

विस्तृत विवरण के लिए लिखें या सम्पर्क करें:

अन्सल हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कं० लि०

2 चायना बाज़ार रोड (तुलसी सिनेमा के पीछे)
लखनऊ-226001, फोन: 48554.
पंजीकृत कार्यालय: 15 अपर ग्राउन्ड फ्लोर, इन्द्र प्रकाश
21 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन: 331-7015, टेलेक्स: 031-62626 ANSL IN.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

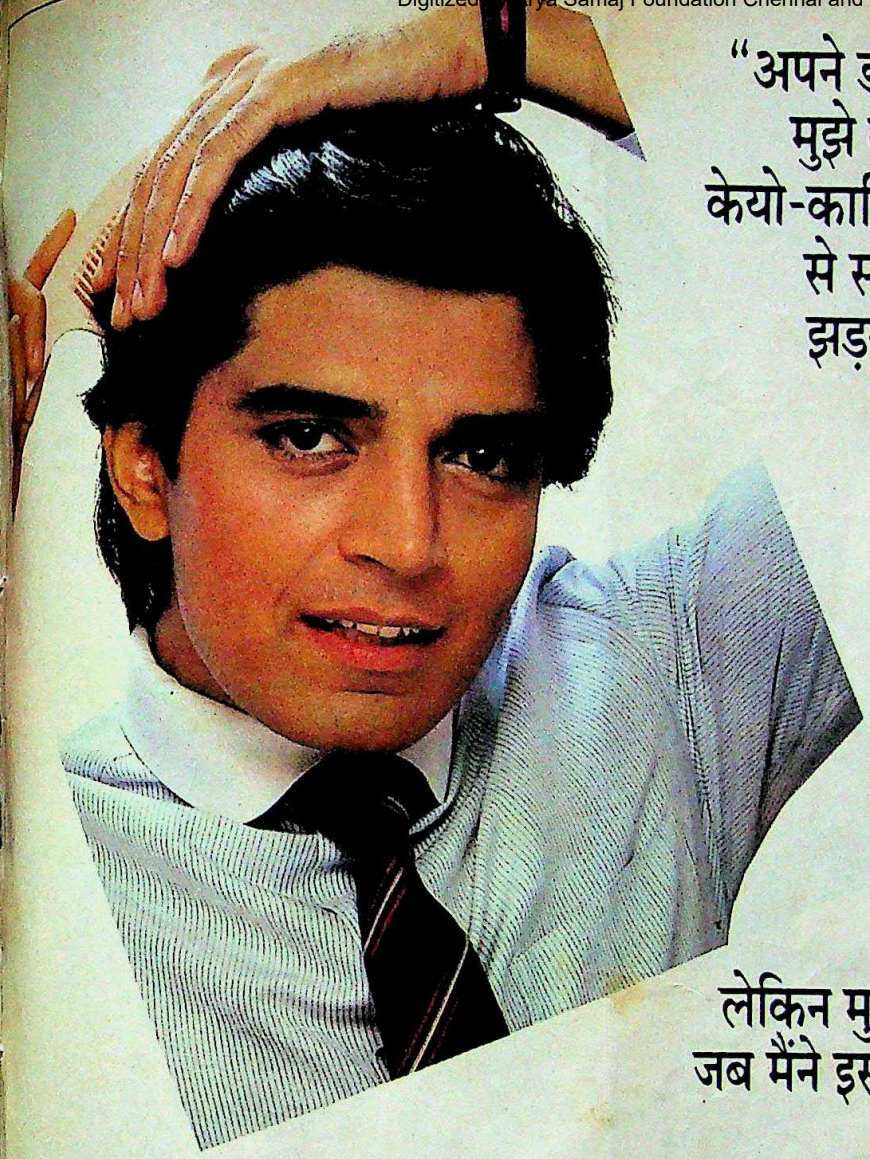

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्ज़ाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३%में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's

दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

DMHV-4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

◆ दूसरों की धुनों पर नाचने वाला और हिंदुस्तानी गरीबों का माइकल जैक्सन यानी **मिथुन चक्रवर्ती** अब अपनी ही धुनों पर थिरक रहा है. 'द इंडियन जैक्सन: मिथुन' के नाम से उन्होंने अपने सात पॉप गीतों का एक नया रिकार्ड तैयार किया है जिसमें रॉक गीतों और गजल के अलावा बच्चों का एक नर्सरी गीत भी है. रिकार्ड तैयार करने वाली सुपर कैसेट म्यूजिक कंपनी के प्रबंध निदेशक गुलशन कुमार का कहना है, "मिथुन की इमेज तो एक रोमांटिक डांसर और ही-मैन की इमेज है. वह सचमुच एक जोरदार गायक है." इस महीने यह रिकार्ड जारी होने के बाद बाजार में मिथुन के अपने ही गीतों पर उनके ब्रेकडांस वाला वीडियो कैसेट भी लाया जा रहा है. देसी माइकल जैक्सन जिंदाबाद!

मिथुन और गुलशन: ही-मैन

◆ अर्जेंटीना की प्रथम महिला और वहां के डिक्टेटर युआन पेरों की पत्नी एविटा की भूमिका निभाने वाली **शेरोन प्रभाकर** अब अपने पति **एलक पदमसी** की नई फिल्म में नए रंग दिखाने जा रही हैं. ब्राडवे के एक नाटक के इस नए संस्करण में भारतीय सांप्रदायिकता पर भी कटाक्ष है. इस बारे में पदमसी कहते हैं, "कहानी में गीत और संगीत के माध्यम से राजनैतिक कटाक्ष पेश किया गया है." मास्को में एक पॉप संगीत कार्यक्रम पेश करने के बाद भारत लौटीं प्रभाकर सैली बाउल्स की भूमिका निभा रही हैं जिन्हें लिजा मिनेली के अभिनय से पहले ही ख्याति मिल चुकी है. वे कहती हैं, "सैली का चरित्र बहुत तेजतर्रार और उलझन भरा है. इसलिए मुझे भी उसके मुताबिक बनना होगा."

◆ यह उस अमेरिकी सितारे की बात है जिसने खुद को भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित करने का फैसला किया है. पिछले पखवाड़े जब तिब्बत के पूर्व शासक दलाई लामा 'कालचक्र' समारोह के सिलसिले में लद्दाख की खूबसूरत जांस्कार घाटी में थे तब 'एन अफसर ऐंड ए जेंटलमैन' और

गेअर: बुद्धं शरणं गच्छामि

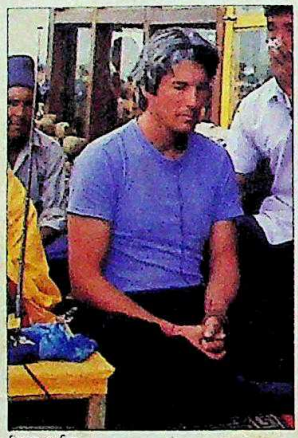

विजय क्रान्ति

'माइल्स फ्रॉम होम' की ख्याति वाले **रिचर्ड गेअर** उनके साथ लगातार ध्यानमुद्रा में बैठकर माला जपते रहे. उनका कहना था, "हम फिल्मी लोग जानते ही नहीं जीवन क्या है? बौद्ध धर्म ने मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया है." वे इन दिनों न्यूयॉर्क में तिब्बती संस्कृति का एक विशेष केंद्र 'तिब्बत हाउस' स्थापित करने में जुटे हुए हैं.

प्रभाकर: नया रंग

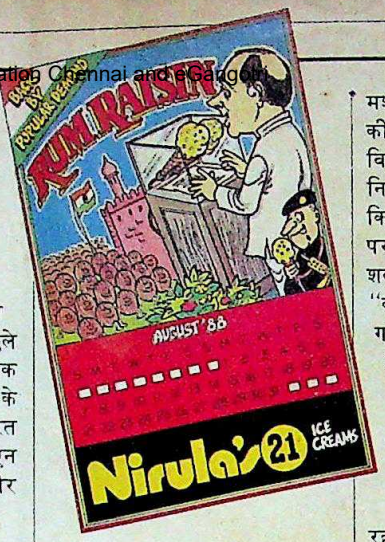

निरुला का पोस्टर: विज्ञापनबाजी की कला

◆ लाल किले की प्राचीर से आइसक्रीम कोन वाले माइक्रोफोन पर कौन भाषण दे रहा है? आगे विशाल जनसमूह और पीछे ब्लैक कैट कमांडो मुस्तैदी से हाथ में आइसक्रीम का एक कोन पकड़कर चाटता हुआ खड़ा है. यह कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि दिल्ली के मशहूर निरुला आइसक्रीम पार्लर की **रम-रेजिन आइसक्रीम** का ताजा विज्ञापन है. सिर के पीछे दो गंजे निशान देखकर आप भले ही मानें कि यह चित्र राजीव गांधी का है पर इस फास्टफूड शृंखला के निदेशक दीपक निरुला का सवाल है, "कौन कहता है कि यह राजीव गांधी हैं? यह तो कोई भी राजनेता हो सकता है." वे कहते हैं, "मुझे नहीं मालूम कि राजीव हमारी आइसक्रीम के फैन हैं या नहीं. हमारा पोस्टर तो केवल सामयिक ही है, बस." कहिए प्रधानमंत्री महोदय! कैसा रहा आइसक्रीम का स्वाद?

◆ **अमृता शेरगिल** को गुजरे अरसा हो गया पर उनकी कलाकृतियां अभी भी लुभाती हैं. हाल ही में शेरगिल की एक मूल कलाकृति की बिक्री के लिए विज्ञापन छपा तो कला व्यवसायी और कला प्रेमी दक्षिण दिल्ली के उस मकान की तरफ दौड़ पड़े जहां कलाकृति रखी गई है. इसकी कीमत 6 लाख रु. है. राष्ट्रीय कला दीर्घा इसे

प्रशांत पंजियार

शेरगिल की कलाकृति

खरीदना चाहती है लेकिन 3 लाख रु. में ही. रिश्ते में शेरगिल के भाई की पत्नी मार्गरेट मजीठिया की तरफ से, जो इस कलाकृति की मालिक हैं, इसे बेचने वाले मेजर जनरल छाची का मानना है कि एम.एफ. हुसैन की कलाकृति लाख रु. में नीलाम हो सकती है तो शेरगिल की क्यों नहीं? शेरगिल विलेज ग्रुप नाम का यह चि 1938 में बनाया था. इसमें अजंत से प्रभावित तांबई रंग की महिला दिखाई गई हैं और उन पर शास्त्र भारतीयता की छाप है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंजिल अभी कोसों दूर

भारतीय ओलंपिक दल सिओल के लिए उड़ा तो देश के खेल जगत की चिरस्थायी समस्याएं फिर सामने आ गईं. राजनीति, कुप्रबंध, विवाद और गिरते स्तर ने कामयाबी के रास्ते में कई बाधाएं खड़ी कर रखी हैं. इन्हें पार कर पाना शायद मुश्किल हो.

आवरण कथा.....50

चौथे खंभे पर चोट

गलत सलाह पर लाया मानहानि विधेयक राजीव गांधी के लिए बहुत भारी पड़ा. समाचार चार माध्यमों ने अपनी एकता का दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए विधेयक का विरोध किया तो राजीव को राज्यसभा में इस पर विचार रोकना पड़ा. पर उनकी साख को तो बट्टा लग ही.

खास रपट.....18

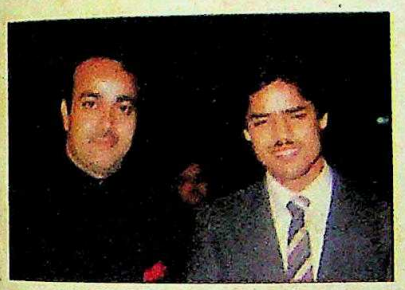

रिश्तों व राजनीति की गुत्थी

संजय सिंह की गिरफ्तारी से लगता है कि सनसनीखेज सैयद मोदी हत्याकांड एक बड़े राजनैतिक विवाद की शक्ल अख्तियार कर लेगा. इस घटना पर एक खोजपूर्ण रिपोर्ट और साथ में अमिता मोदी तथा संजय सिंह की पत्नी गरिमा से बातचीत.

खास रपट.....22

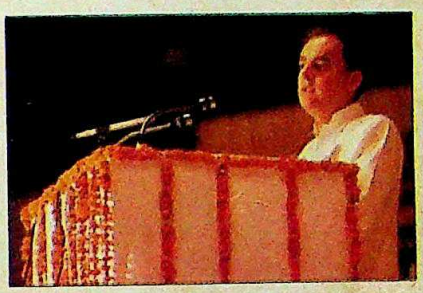

जान फूंकने की जद्दोजहद

कांग्रेस (इ) अगले आम चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है. पिछले बिनों पार्टी की राष्ट्रीय संगोष्ठी में इसी मसले पर विचार हुआ. लेकिन पार्टी अपने नेतृत्व के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगी? एक विश्लेषण.

खास रपट.....28

ढर्रे पांव आता हुआ बदलाव

कारखानों में काम की जापानी शैली अब भारतीय कंपनियां भी आजमाने लगी हैं. यूकोसो शैली में काम शुरू करने से पहले कारखाने में कहीं मजदूरों से व्यायाम कराया जाता है तो कहीं मजदूरों और फोरमैन के बीच उत्पादन लक्ष्यों के बारे में विचार-विमर्श होता है.

कारोबार.....66

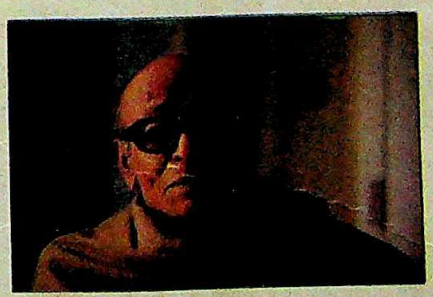

खयाल गायकी के धुरंधर

मल्लिकार्जुन मंसूर '30 के दशक के शुरू से शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को अपने अनूठे खयाल गायन से मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं. उनकी गायकी की शैली ने गायकों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रभावित किया ही है, कंठ और सुर के बीच की कुछ सीमाओं को भी तोड़ा है.

छाया लेख.....76

अगले पन्नों पर

कसौटी.....8
राजरंग.....10
तेवर.....11
हिंदोस्तां हमारा.....12
बीता पखवाड़ा.....17
खास रपट
मानहानि विधेयक: चौथे खंभे पर चोट....18
मोदी हत्याकांड:
रिश्तों व राजनीति की गुत्थी.....22
कांग्रेस (इ): जान फूंकने की जद्दोजहद....28
आजकल
नौकरशाही: बेमानी तरक्कियां.....31
मिजोरम: असंतोष और अनिश्चय.....32
डीडीए: बालू से बनाए गए बसेरे.....34
महाराष्ट्र: धमकी भरा टेप.....36
बिहार: बासदी में तमाशा.....37
एनसीपीए: मंजूरी पर विवाद.....38
अजिताभ बच्चन: दाग धोने का नाटक.....39
बात पते की.....40
उड्डयन
विजयपत सिंघानिया: जोखिम भरी उड़ान....41
खास रपट
आंध्र प्रदेश: बाजी उलटने से बड़ा फायदा..42
राज्य-दर्पण.....45
जगबीती
न्यूयॉर्क: लापरवाही में होता घाटा.....47
कूटनीति
इस्राएल: नाजुक रिश्ते में नया मोड़.....48
आवरण कथा
सिओल में भारत:
मंजिल अभी कोसों दूर.....50
व्यापार चक्र.....63
कारोबार
कंपनियों की खरीद:
पुराने खेल में नया जोश.....64
कार्यपद्धति:
ढर्रे पांव आता हुआ बदलाव.....66
विज्ञापन: बच्चों के जरिये बड़ों तक.....70
थापर समूह: माफी फिर सजा.....72
रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स:
आशातीत सफलता.....73
सांबर: विदेशी दाल, देसी जायका.....74
शेयर बाजार.....75
छाया लेख
मल्लिकार्जुन मंसूर:
खयाल गायकी के धुरंधर.....76
खेलकूद
इंग्लैंड दौरा: खटाई में पड़ने का खतरा....88
सिनेमा
सुहासिनी-रत्नम: गांठ बंध गई.....93
रंगमंच
हिंदी थिएटर:
विदेशी नाटकों की बैसाखी.....94
टीवी
भारत: एक खोज:
इतिहास की वीथिकाओं में.....96
किताबें.....99
धरोहर
राष्ट्रीय संग्रहालय: रूसियों की सौगात....102
चर्चित चेहरे.....104

आवरण: रघु राय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहली नज़र में फ़िदा.

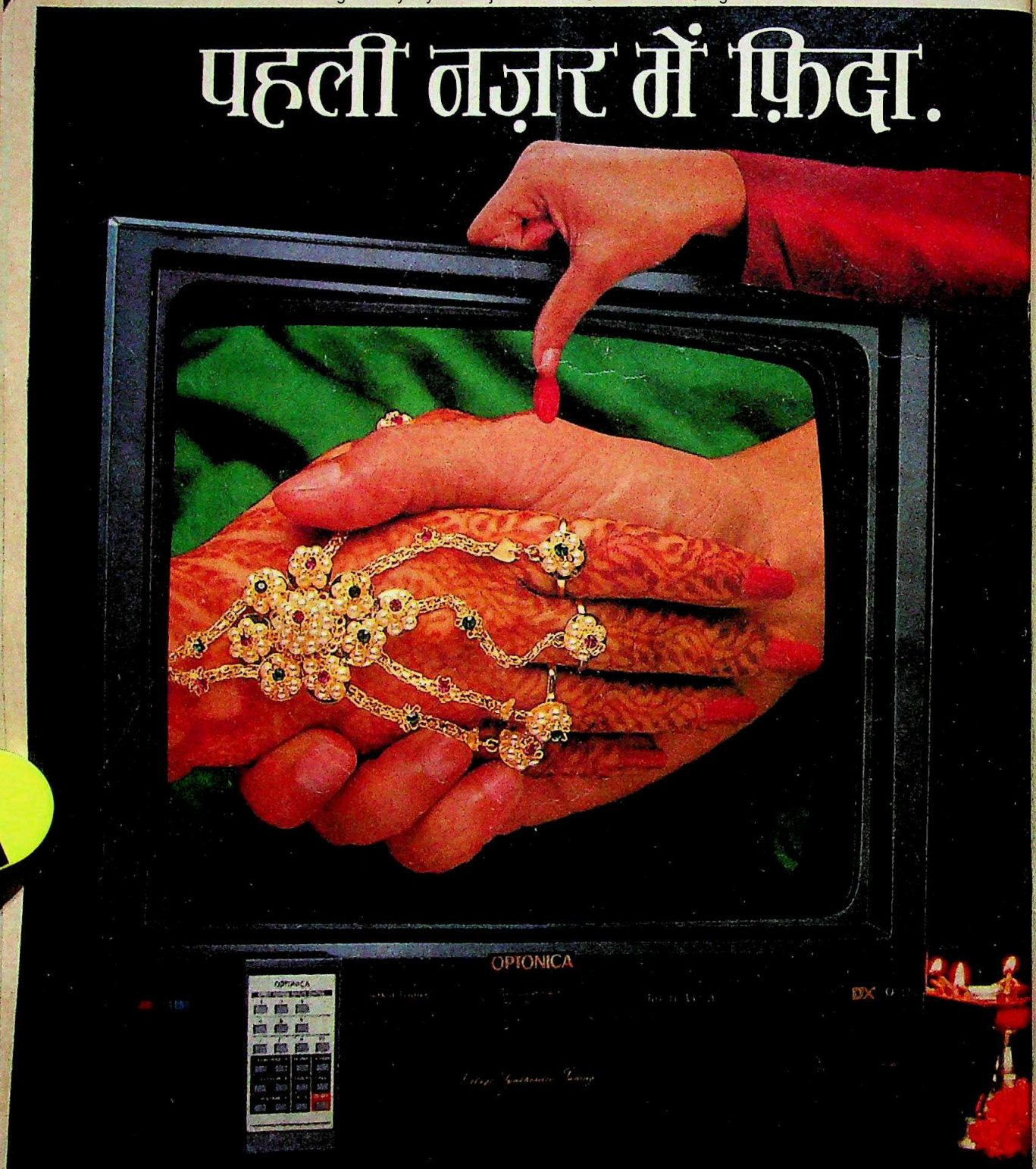

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भारत में निर्माता : **कल्याणी शार्प इंडिया लि.**

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बस, नज़र पड़ते ही आप जी-जान से न्यौछावर... यही तो है ऑप्टॉनिका का करिश्मा... जीवन भर के लिए... ऑप्टॉनिका, एकमात्र टीवी, जो आपकी नज़रों के सामने **ट्रू-लाइफ़ विज़न** का ख़ज़ाना खोलने को तैयार है.

ट्रू-लाइफ़ विज़न – सच्चाई का दर्पण... तराशी तस्वीरें... स्पष्ट और तीखी... **हाइ सेन्सिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर** की बदौलत, **कलर डिकोडर सर्किट** के कारण नैचुरल रंगों का स्वाभाविक दर्शन, **ऑटो लिनियरिटी कंट्रोल** की वजह से सही आकार... सही स्वरूप. **ऑप्टिमैटिक पिक्चर कंट्रोल** याने कॉन्ट्रास्ट का खुद-ब-खुद फिर से ठीक और व्यवस्थित हो जाना.

ऑप्टॉनिका – सुंदर, भरोसेमंद – जीवन भर के साथ का वायदा लिए...
ऑप्टॉनिका – पहली नज़र में ही आप इसके हो जाएंगे!

OPTONICA

ट्रू-लाइफ़ विज़न... ज़िन्दगी भर के लिए!

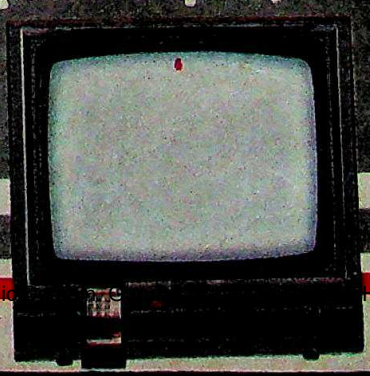

CC-0. In Public ... Haridwar

Mudra : B : BF : 4969 HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रानूट्रोल हंसा एक्वा मिक्सर.
मनचाहा गर्म, गुनगुना या ठंडा पानी पाने का सरलतम तरीका.

और रानूट्रोल हंसा एक्वा मिक्सर में यह सब संभव है केवल एक लीवर से — जिसे घुमाने भर से मिले मनलायक ठंडा या गरम पानी — आप बस गुनगुनाते रहें रानूट्रोल हंसा के गुण। इसी लीवर को ऊपर करते ही आप जितनी चाहें पानी की उतनी तेज़ धार और नीचे दबाने पर धीमी-धीमी धार। है न सरल तरीका।

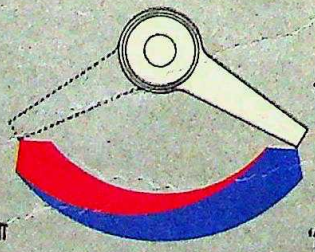

यह कमाल है विश्व में एक्वा मिक्सर के सबसे बड़े विक्रेता, हंसा मैटलवर्क ए.जी. की 'सिरामिक कारट्रिज' तकनीक का।

आप भी अपने बाथरुम में नहाने गुनगुनाने का मज़ा लेना चाहते हैं या किचन में मनचाहे पानी की सुविधा तो चुनिये आकर्षक डिज़ाईनों में से, अपना मनपसन्द रानूट्रोल हंसा।

RANUTROL HANSA
AQUA MIXER
From Hansa Metallwerke AG, West Germany.

मुफ्त जानकारी पुस्तिका के लिये लिखिये : ऑटो कंट्रोल्स प्रा॰ लि॰, 414, न्यू देहली हाऊस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001. टेली॰ : 331 6464/0137.
ब्रान्च आफिस (टेली॰) — बम्बई : 492 7125, 492 0297, 23 3629, 23 4424. कलकत्ता : 29 1755. मद्रास : 47 6723. बैंगलौर : 57 8846.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इंडिया टुडे
सप्ताह समाचार पत्रिका

वर्ष 2, अंक: 22, 16-30 सितंबर 1988

प्रधान संपादक
अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक
प्रभु चावला

संपादकीय विभाग
जगदीश उपासने, अशोक कुमार,
विजय क्रांति, ओम प्रकाश सराफ,
अरविंद मोहन मिश्र

प्रोडक्शन
अनिल शर्मा, सुबाचन यादव
सुनील सैनी

■ **संपादकीय कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली.

■ **मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:** इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

■ **मुख्य विज्ञापन कार्यालय:** 28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029436, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया, बंबई.

■ **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली • फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास • 74/1 सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर • 12-सी, वेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता. • कॉपीराइट © 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता. • लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

नेपाल में 6 रुपए

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजीव गांधी सत्ता में आए थे तो प्रेस जगत ने मानो उनके हाथ चूम लिए थे. आज वही हाथ बंधी मुट्ठी बनकर प्रेस को झुकाने को धौंसबाजी पर तत्पर हैं.

मानहानि विधेयक के द्वेषपूर्ण प्रावधानों के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है. पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू की ओर संकेत कहीं नहीं दिखता. वह यह कि भारी बहुमत से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार ऐसे हताशाजनक मोड़ पर पहुंच गई है जहां वह आजादी की मूल धारणा—अभिव्यक्ति की आजादी—को कुरबान करने को तैयार खड़ी है. अपने तुच्छ राजनैतिक हितों की खातिर उसने दुष्ट राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल होने का जोखिम भी उठा लिया है.

इससे सरकार के इस रुझान की कलई खुल गई कि वह अपने क्रियाकलाप सुधारने के बजाय आलोचनाओं का ही गला दबाना चाहती है. मामला और भी खेदजनक है. सरकार के क्रियाकलापों से यह उजागर हुआ कि भारी बहुमत के बलबूते पर वह किस सफाई से भारतीय लोकतंत्र को बांधे रखने वाले धागों को तार-तार करने की सीमा तक जा सकती है. अगर यह विधेयक कहीं पहले कानून बन गया होता तो घूस और भ्रष्टाचार के रहस्योद्घाटन मुमकिन ही न हो पाते या फिर ऐसा करने वालों को फौजदारी कानून की चक्की में पिसना पड़ता. ये रहस्योद्घाटन ही इस अंधे विधेयक की वजह भी हैं. अगले साल होने वाले आम चुनावों से घबराई सरकार को शायद यह उम्मीद थी कि विधेयक पारित करवाकर वह और रहस्यों को उधड़ने से बचा लेगी. विधेयक लाने में जो अशोभनीय जल्दबाजी और गोपनीयता बरती गई तथा उसके हक में जैसी बेशर्म लफ्फाजी हुई उनसे सरकार के कुत्सित इरादों का पर्दाफाश अपने आप ही हो जाता है.

रेखाचित्र: अजीत नैनन

इस वैधानिक शैतानी के रचयिताओं को उम्मीद नहीं थी कि विधेयक के विरोध में जनता प्रेस की अगुआई में एकजुट हो जाएगी. बिना राजनैतिक भेदभाव के देशव्यापी विरोध को देखकर सरकार ठगी-सी रह गई. अब उसने, जैसा कि फंस जाने पर वह अक्सर करती है, विधेयक को 'स्थगित' कर दिया है. उसने प्रेस से अपनी सात सदस्यीय समिति के लिए सुझाव भी मांगे हैं. यह वैसा ही आचरण है जैसे पहले किसी के पेट में छुरा घोंप दो और फिर उसे यह विचार-विमर्श करने के लिए न्यौता दो कि छुरा वहीं रहे या कुछ इंच पीछे खिसका लिया जाए.

जब सरकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति को अपराध का दर्जा देना चाहे तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचती. इस विधेयक को गहरे दफना दिया जाना चाहिए. सरकार को समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में हर बात एक समान नहीं हो सकती. इसमें अखबार एक ही सुर में यदा-कदा ही बोलते हैं. यह एक ऐसी घालमेल भरी व्यवस्था है जिसमें जिम्मेदार और गैर-जिम्मेदार, उग्र और शालीन एक साथ रहते हैं. और अंततः जिम्मेदार लोगों का हाथ कम भरोसेमंद लोगों से ऊपर हो जाता है. राजनीतिकों और सरकारों को लोकतंत्र की असुविधाओं से तालमेल बिठाना ही पड़ेगा. यह कीमत चुकानी ही होगी. जैसा कि हैरी ट्रूमैन ने एक दफा कहा था, "अगर आप गरमी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रसोईघर में आपका क्या काम?"

अरुण पुरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

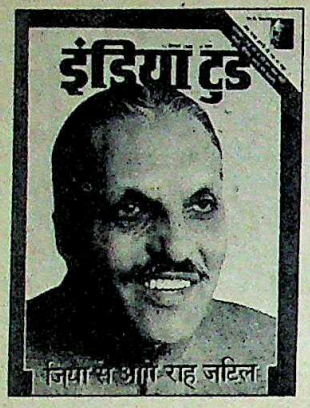

दाग दिखेंगे

आवरण कथा 'जिया से आगे राह जटिल' (15 सितंबर) निश्चय ही प्रभावशाली रिपोर्टिंग की अनूठी मिसाल है. जिया का यह कथन कि 'इतिहास मेरा निष्पक्षता से आकलन करे', उनके लिए भारी ही पड़ेगा क्योंकि निष्पक्षता से आकलन करने पर उनकी फौजी वर्दी पर काले धब्बे ही अधिक मिलेंगे. निजी प्रभाव बढ़ाने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने जो तनाव उत्पन्न किया वह पूरे क्षेत्र के लिए घातक है.

—राकेश मिश्र, लखनऊ (उ.प्र.)

■ आपकी समीक्षा निष्पक्ष लगी. लेकिन पाकिस्तान के भविष्य के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल ही है क्योंकि सत्ता एक तानाशाह सैनिक के हाथ से दूसरे सैनिक के हाथ में आई है.

—सत्यप्रकाश द्विवेदी, बुलंदशहर (उ.प्र.)

भले की आशा

अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में 'पांसा पलटने की पुख्ता संभावना' (15 सितंबर) भारत के लिए हितकारी सिद्ध हो सकती है. अतीत गवाह है कि ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ सौतेला व्यवहार किया है. ऐसे में डेमोक्रेट डुकाकिस का जीतना भारत के लिए लाभप्रद ही रहेगा.

—पुनीत जोशी, सीकर (राज.)

राजनीति कैसी

'हत्या की राजनैतिक जांच' (15 सितंबर) पढ़ा. यह कहना कि इस घटना को राजनैतिक चोला पहनाया जा रहा है सही नहीं है. यदि संजय सिंह दोषी नहीं हैं तो उन्हें यह गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की मदद करनी चाहिए. वैसे भी जब तक सबूत न हो, सीबीआई किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती.

—विजय पाल, बरेली (उ.प्र.)

बेहतर मिसाल

'मुखौटे बदलती व्यवस्था' (15 सितंबर) में फिल्म 'अंधा युद्ध' की समीक्षा बहुत अच्छी लगी. आज राजनीति पतन की किन नीचाइयों को छू रही है, इसका इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता. हैरानी की बात है कि अब फिल्म सेंसर बोर्ड ने भी राजनीतिकों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है.

—दीपक मलिक, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

सराहनीय अभियान

'जहर के खिलाफ जंगी जेहाद' (15 सितंबर) सचमुच सराहनीय है. आखिर युवाशक्ति को खोखला होते कब तक देखा जा सकता है. परंतु यह अभियान मात्र एक सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए. इसके लिए नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा प्रचार साधनों का सहयोग बहुत जरूरी है क्योंकि इस 'अति लाभप्रद' धंधे से जुड़े लोग अपने हाथों से सोने की चिड़िया को आसानी से फिसलने नहीं देंगे.

—संजीव कश्यप, बुबकपुर (उ.प्र.)

चोला बदले

आवरण कथा 'तेजी से घटती लोकप्रियता' (31 अगस्त) अत्यंत रोचक और तथ्यपूर्ण थी. जनमत संग्रह के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष यदि देश में सत्ता परिवर्तन चाहता है तो उसे विवादों और मतभेदों से दूर रहकर असंभव हो चली विपक्षी एकता को संभव कर दिखाना होगा. कुछ स्थानों की जीत से उसे यह नहीं मान लेना चाहिए कि अब वह सत्ता में आने में समर्थ है. इसके लिए नैतिक और राजनैतिक मजबूती की जरूरत है जो फिलहाल उनके पास नहीं है.

—संजय कुमार गलांडे, आगरा (उ.प्र.)

■ आपने बहुत कम शब्दों में बहुत-सी बातें कहकर मतदाताओं को कुछ सोचने को विवश कर दिया है लेकिन विपक्षी एकता अभी भी एक मृग-मरीचिका ही है. इन लोगों के पास न तो समग्र कार्यक्रम है न ही कोई नीति. विपक्ष का अब तक का एक सूत्री कार्यक्रम 'राजीव हटाओ' ही है. अब बताइए मतदाता विपक्ष को वोट कैसे दें और क्यों दें?

—जितेंद्र रामपुरिया, रायपुर (म.प्र.)

■ यह भी विडंबना ही है कि 'स्वच्छ' और 'साफ-सुथरा' प्रशासन देने के वायदे से सत्ता में आई राजीव सरकार ही सबसे ज्यादा घोटालों और भ्रष्टाचार से घिरी साबित हुई है.

—उदयवीर सिंह, मथुरा (उ.प्र.)

■ यह कहना शायद ठीक नहीं कि राजीव की लोकप्रियता घट रही है. वह अभी भी जहां जाते हैं लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है. विपक्ष की एकता राजीव के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि राजीव समेत सभी लोग जानते हैं कि साझे की हंडिया बीच चौराहे पर ही फूटती है जैसे यह 1977 में जनता-प्रयोग के बाद फूटी थी.

—विजय सिंह, हलद्वानी (उ.प्र.)

■ राजीव गांधी की लोकप्रियता जितनी भी तेजी से घटे, यदि विपक्ष आपस में लड़ता रहा तो वह कभी भी इंका को नहीं हरा सकेगा. इंका को हराने के लिए जरूरी है कि विपक्षी नेता अपने तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर एक नेता का चयन करें.

—अनिल चंद्राकर, भोपाल (म.प्र.)

नैतिक साहस

'मूल्यों की महंगी कीमत' (31 अगस्त) चुकाकर हेगड़े ने साबित कर दिया कि उनमें सत्तालोलुपता नहीं है. जिन राजनैतिक मूल्यों की वे बातें करते हैं उन्हें व्यवहार में लाने का नैतिक साहस भी उनमें है.

—निर्मेष जैन, मेरठ (उ.प्र.)

■ टेलीफोन टेप कांड की नैतिक जिम्मेदारी मानकर अपने पद से त्यागपत्र देकर हेगड़े ने भारतीय राजनीति में एक राह तो खोली ही है, बोफोर्स, फेयरफैक्स, पनडुब्बी सौदे जैसे घोटालों से घिरे और ढिठाई से उन करतूतों पर परदा डालने में लगे नेताओं के सामने उदाहरण भी पेश किया है.

—पवन शर्मा, इंदौर (म.प्र.)

ओछी हरकत

'बदनामी के छींटे' (31 अगस्त) में पंजाब पुलिस महानिरीक्षक गिल ने भारतीय पुलिस की ऐसी छवि प्रस्तुत की है जो समाज का रक्षक कम, भक्षक अधिक हो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चला है. शर्म की बात है कि सरकार ने जिसे इतनी बड़ी मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी, वह इतनी ओछी हरकत पर उतर आया. बजाज का अपने निश्चय पर अड़े रहना सराहनीय है. —**कौशल किशोर शुक्ल**, कपिलवस्तु (नेपाल)

■ पंजाब पुलिस महानिदेशक के.पी.एस. गिल की हरकत पढ़कर सिर शर्म से झुक गया. देश का प्रशासक, जनता का संरक्षक वर्ग यदि ऐसी अशोभनीय हरकतों पर उतर आता है तो बाकी लोगों का भगवान ही मालिक है. —**सुरेंद्र रौथाण**, उत्तरकाशी (उ.प्र.)

■ गिल साहब ने पुलिस विभाग को जो बधाएं दी हैं उसको नकारा नहीं जा सकता लेकिन यह बात कल्पना के परे लगती है कि एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार पुलिस अधिकारी के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू ऐसा होगा. —**मन्नू सिहारे**, मंडला (म.प्र.)

विस्तृत जानकारी

'जीते हैं शान से, मारते हैं जान से' (31 अगस्त) बहुत रोचक लगा. पहली बार मच्छरों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिली. यदि इन मच्छरों का नाश नहीं हुआ तो यह मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित होंगे.

—**मनीष झोकरकर**, भोपाल (म.प्र.)

अन्यायपूर्ण

नगालैंड में विधानसभा भंग कर और राष्ट्रपति शासन लागू कर सचमुच 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ताक पर' (31 अगस्त) रख दिया गया. नगालैंड में राज्यपाल की यह दलील कि 'राज्य सरकार को संविधान की शर्तों के अनुसार चलाना मुमकिन नहीं रहा' तर्कहीन, अन्यायपूर्ण तो है ही, लोकतांत्रिक उसूलों पर कुठाराघात भी है. नगालैंड के लोगों को भी अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए बहुमत के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों को सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए.

—**नारायण प्रकाश कर्ण 'नारंग'**, मोन (नगालैंड)

■ नगालैंड में केंद्र की राजनैतिक कारगुजारियों से स्पष्ट है कि इंका सत्ता के लिए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ करने में जरा भी नहीं हिचकती. पंजाब में जिस गलती का नतीजा आज गंभीर चुनौती के रूप में खड़ा है, नगालैंड जैसे संवेदनशील राज्य में तो राजनैतिक अस्थिरता के और भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं. —**अनित**, मुल्हेड़ा (उ.प्र.)

अच्छा लक्षण

'पुराने दिग्गजों की नींद टूटी' (31 अगस्त) पढ़ा. पिछले वर्षों से भारतीय हाकी में जो शून्य पैदा हुआ है उसके लिए दोषपूर्ण चयन, राजनीति, उचित प्रशिक्षण का अभाव व शैली में बार-बार किए जाने वाले परिवर्तन ही जिम्मेदार हैं. फिर भी पुराना गौरव दोबारा हासिल करना कठिन नहीं है.

—**कल्याणदास माहेश्वरी**, बड़नगर (म.प्र.)

■ हाकी के बारे में पढ़कर सिर्फ निराशा ही होती है. विश्व पर एकछत्र राज करने वाला भारत आज अंतिम स्थान पर है. सरकार निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार है. यूरोपीय देशों में जहां सैकड़ों ऐस्ट्रो टर्फ हैं, हमारे देश में ऐस्ट्रो टर्फ तो दूर साधारण मैदान तक उपलब्ध नहीं हैं.

—**मुहम्मद अयूब**, रुड़की (उ.प्र.)

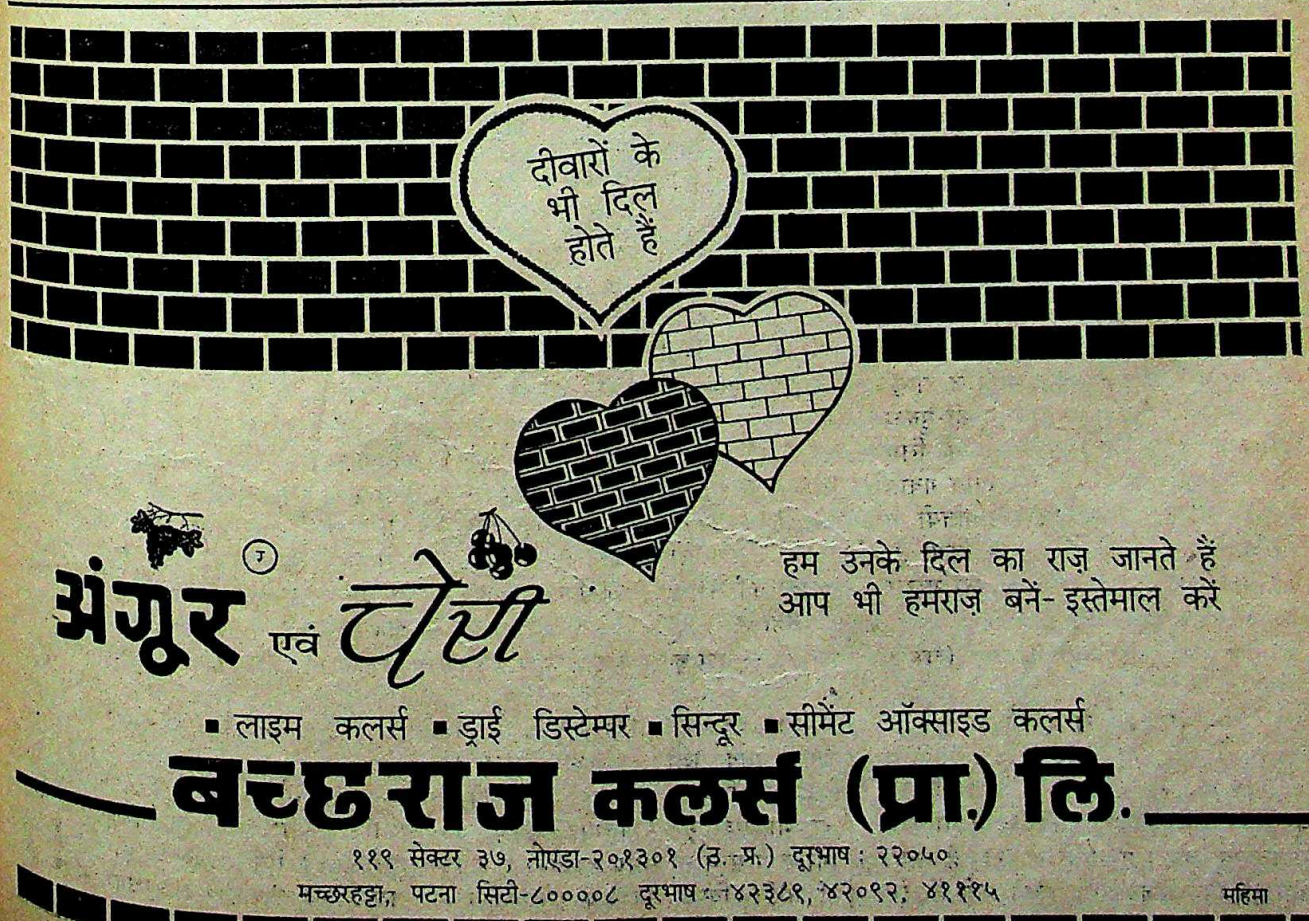

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

नए हालात, नई चुनौतियां

किस राह चल पड़ा है दक्षिण एशिया? भारत के पड़ोस में चारों तरफ अचानक अपूर्व अनिश्चितता और उथलपुथल के आसार दिख रहे हैं. सीमा पार पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक के निधन से तमाम क्षेत्रीय समीकरण उलटपुलट-से गए हैं. फिलहाल तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान की अवाम को जम्हूरियत का जायका मिलने वाला है. वहां लोकतंत्र कायम हो गया तो भारत-पाक के भावी रिश्तों पर नाटकीय असर पड़ेगा.

उधर विस्मृत-से कर दिए गए पड़ोसी देश बर्मा में भी ऐसे ही भारी परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं. वर्षों तक तानाशाही झेलने के बाद वहां की जनता ने लोकतंत्र के लिए जबरदस्त मुहिम छेड़ दी है. वहां भी लोकतंत्र कायम हुआ तो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी.

जिया के अचानक अवसान के बाद अफगानी बागियों को अमेरिकी सैनिक मदद जारी रखने पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है. और अब डॉ. नजीबुल्ला के कुछ और दिनों तक सत्ता में बने रहने की संभावनाएं भी बलवती हो गई हैं.

उधर श्रीलंका में राष्ट्रपति जयवर्द्धने और उनकी सरकार की तेजी से घटती लोकप्रियता के कारण सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ती जा रही है. ऐसे में भारतीय शांति सेना अजीब पशोपेश में फंसती दिख रही है

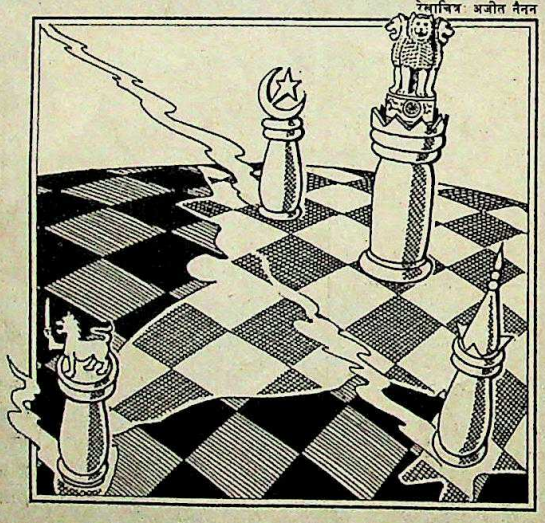
रेखाचित्र: अजीत नैनन

यानी इन देशों में परिवर्तनों के जो संकेत हैं उनके कारण भारतीय विदेश नीति आजादी के बाद पहली बार किसी बड़ी चुनौती से रूबरू है. पड़ोसी देशों के बीच 'सरपंच' की उसकी हैसियत को वर्षों से संदेह से देखा जाता रहा है. लेकिन अब ऐसे संयोग बन रहे हैं कि वह अपनी इस छवि को सकारात्मक स्वरूप दे सके. दक्षिण एशिया में एक बड़ी ताकत होने का कूटनीतिक लाभ उठाने का सबसे उपयुक्त अवसर अभी ही आया है. इस पूरे क्षेत्र में हो रहे उथलपुथल से भारत के बारे में यह धारणा और मजबूत ही हुई है कि यह एक ऐसा विशाल और सशक्त देश है जिसके स्थायित्व पर राजनैतिक या आंतरिक उथलपुथल का कोई खास असर नहीं पड़ता.

लेकिन क्या भारतीय विदेश विभाग में इन नए संयोगों का लाभ उठाने की कुव्वत है. पाकिस्तान के साथ संबंधों की हालत वही जानी-पहचानी है. वहां भारत दबंग 'बड़े भाई' की भूमिका निभाएगा तो इससे उलझन बढ़ ही सकती है. निकट भविष्य में तो कुछ फायदे हो सकते हैं लेकिन अंततः नुकसान ही होगा. इन दोनों देशों के भावी रिश्ते आगामी कुछ निर्णायक महीनों में भारत की भूमिका से बहुत हद तक प्रभावित होंगे. पाकिस्तान को यदि विश्वास हो जाए कि उसके मौजूदा हालात के चलते भारत उसे कमजोर करना चाहता है तो वहां चाहे बेनजीर की सरकार हो या जुनेजो की, वह पंजाब को तुरुप का पत्ता बनाने से नहीं हिचकेगी. इस चाल के नतीजे उसके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं.

बर्मा ने वैसे तो अलग-थलग रहने की नीति अपनाए रखी है. लेकिन इस क्षेत्र में भारत ही शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसने उसके साथ लगातार कूटनीतिक संबंध बनाए रखा है. इस कारण भारत अपने महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र के पार एक विश्वसनीय मित्र की अपेक्षा तो रख ही सकता है.

इन तमाम तथ्यों का एक बड़ा कूटनीतिक लाभ यह भी है कि इस क्षेत्र में चीन का असर घटता है. क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने की उसकी क्षमता कमजोर होती है. पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना से चीन की स्थिति और कमजोर ही होगी. पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते उन रणनीतिक समीकरणों से संचालित थे जो पाकिस्तान के सैनिक शासकों को माकूल बैठते थे.

यानी मुख्य बात यह है कि भारत अगर क्षेत्रीय ताकत बनने की सचमुच इच्छा रखता है या उसमें इसकी क्षमता है तो पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को नया स्वरूप और स्थायित्व देना इस दृष्टि से लाभकारी ही होगा. उसे अपनी मौजूदा 'दबंग' छवि को बदलना होगा. उसे इस उपमहाद्वीप के एक ऐसे विशाल और सशक्त देश की वास्तविक छवि कायम करनी होगी जो इस क्षेत्र को बाहरी दखलंदाजियों से तो आजाद रखना ही चाहता हो, संकट और उथलपुथल के दौर में स्थिरता कायम करने को भी तत्पर हो. वह 'दक्षेस' परिवार में अफगानिस्तान और बर्मा को शामिल कराने की बात भी उठा सकता है ताकि उसकी पकड़ और असर ज्यादा मजबूत हो.

इधर ऐसे संकेत हैं कि भारत अल्पकालिक उपलब्धियों का मोह—जो अब तक उसकी विदेश नीति की 'विशेषता' रही है—छोड़कर दीर्घकालिक उपलब्धियों पर नजर डाल रहा है. श्रीलंका में उसने विपक्षी नेता श्रीमती भंडारनायके पर दांव लगाना शुरू कर दिया है. पूरी संभावना है कि जयवर्द्धने की उत्तराधिकारी वे ही बनें.

अफगानिस्तान की नजीबुल्ला सरकार का पक्ष लेकर भारत ने अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं के विपरीत काम ही किया था. आज अगर जिया जिंदा होते तो इस रवैये को सवालिया निगाहों से ही देखा जाता. मगर जिया के बाद अफगानिस्तान में हालात बदलते हैं तो भारत अपने इस कूटनीतिक फैसले का पर्याप्त लाभ उठा सकता है.

जिया के निधन के बाद पाकिस्तान के प्रति अपने रवैये में भारत ने एक नई परिपक्वता का परिचय दिया है. यह कुछ महीने पहले चल रही पाक विरोधी बयानबाजियों के उलट ही है. इन सब बातों से उम्मीद बंधती है कि भारत इस क्षेत्र में हो रहे उथलपुथल के प्रति जिम्मेदारी और समझदारी का रवैया अपनाएगा. वास्तविक चुनौती 'दबंग' हुए बिना असरदार होने की है. क्या भारतीय विदेश नीति इस कसौटी पर खरी उतरेगी?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शैली बदलेंगे

● प्रधानमंत्री के नए सूचना सलाहकार जी. पार्थसारथी प्रेस से प्रधानमंत्री के रिश्तों को नया रूपाकार देने जा रहे हैं. पार्थसारथी के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि पुरानी व्यवस्था पर मणिशंकर अय्यर की छाप थी और उसकी

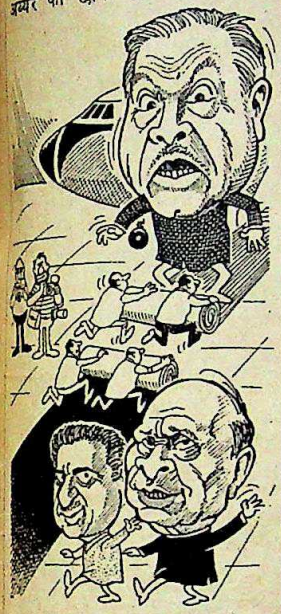

रचनात्मकता खत्म हो गई थी. "लगता था जैसे प्रधानमंत्री को हर चीज रटा दी गई हो. उनके भाषण बहुत औपचारिक होते थे."

अब नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री को अनौपचारिक होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. उनके भाषणों को छोटा और आसान किया जा रहा है. उसमें से 'देखेंगे' को हटाया जा रहा है. अब प्रधानमंत्री, जब कभी मौका मिलेगा, बिना तैयारी के ही बोलेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, "हम इसे राजीव गांधी का कायापलट कहते हैं." नई नीति के तहत खास जानकारियां देने, प्रधानमंत्री से भेंटवार्ताएं करने और विदेशी दौरों पर जाने के मामले में क्षेत्रीय पत्रकारों को तरजीह दी जाएगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने स्वीकार किया है कि इसमें से कुछ बदलाव तो इसलिए किए गए हैं कि आजकल बाजार में एक कैसेट काफी बिक रहा है जिसमें प्रधानमंत्री के बोलने के ढंग की जमकर खिंचाई की गई है. बताया जाता है कि यह कैसेट भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयार किया है. इससे राजीव के सलाहकार विचलित हो उठे. वे मानते हैं कि प्रधानमंत्री की शैली बदलनी चाहिए और यही पार्थसारथी की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

राजपाट छिना

● विदेश सेवा की अफसरी के बाद राजनीतिक का जामा पहन लेने वाले कुंवर नटवर सिंह के सितारे आजकल गर्दिश में हैं. इसकी अपनी वजहें हैं. विदेश राज्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने साल भर तक मुस्तैदी से काम किया. लेकिन पिछले मंत्रिमंडलीय फेरबदल में उनका कद छोटा कर दिया गया.

इससे चंद रोज पहले ही लंदन में हुई एक विशेष दावत में कई हस्तियों ने उन्हें दिग्गज राजनयिक की संज्ञा दी थी. पर उन्हें नहीं मालूम था कि वापस पहुंचते ही इस राजनयिक सितारे को ग्रहण लग जाएगा. उनके एक दोस्त के मुताबिक विदेश मंत्रालय में पी.वी. नरसिंह राव को पूर्ण मंत्री और के.के. तिवारी को अतिरिक्त राज्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाना नटवर सिंह के लिए बज्रपात साबित हुआ. हाल ही में जब मंत्रा-

सभी कार्टून: अजीत नैनन

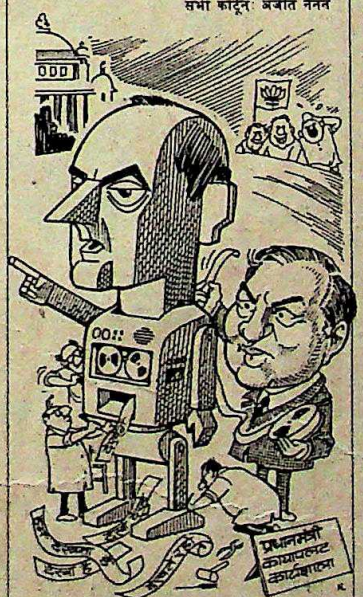

लय में कामों का फिर से बंटवारा हुआ तो वे और भी परेशान हो उठे. कनिष्ठ मंत्री तिवारी को न सिर्फ यूरोप का कार्यभार दिया गया वरन प्रशासन और नियुक्तियों का काम भी सौंप दिया गया. इस तरह राजनयिक विभाग और जिम्मेदारियां बांटने के मामले में तिवारी कुंवर साहब से ज्यादा शक्तिशाली बन गए.

मुक्ति की खुशी

● दो टूक बात करने वाले राजस्व सचिव डी. बंद्योपाध्याय हाल ही में एशियाई विकास बैंक में तबादला होने के बाद से बहुत प्रसन्न बताए जाते हैं. अपने दोस्तों के बीच 'देबू दा' के नाम से मशहूर बंद्योपाध्याय की खुशी फिलीपींस में

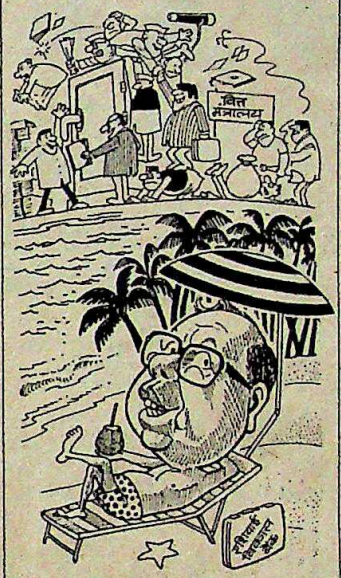

नियुक्ति की वजह से नहीं है बल्कि मंत्रालय की राजनीति से मुक्ति मिलने से है.

राजस्व सचिव के तौर पर बंद्योपाध्याय को राजनैतिक दबाव और खास तरफदारी की सिफारिशों का सामना करना पड़ता था. एक बार उन्होंने एक बड़े उद्योगपति के यहां छापा मारने का आदेश दिया. उस उद्योगपति ने उसी दिन सुबह तिवारी के संग नाश्ता किया था और बंद्योपाध्याय ने छापे का आदेश देने से पहले तिवारी से इस तथ्य की पुष्टि कर ली थी. छापे से बौखलाए उद्योगपति ने तिवारी को अपना दुखड़ा सुनाया तो मंत्री जी ने राजस्व सचिव को आड़े हाथों लिया. बाद में पता लगा कि छापा गलत उद्योगपति पर पड़ गया था. वित्त मंत्रालय के अफसर बताते हैं कि कुछ खास उद्योगपतियों की खातिर प्रधानमंत्री कार्यालय से राजस्व सचिव को अक्सर फोन आते रहते थे. तबादले से कुछ पहले ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने बंद्योपाध्याय को सलाह दी थी कि वे बड़े उद्योगपतियों की एक सूची बनाएं और फिर तिवारी से पूछें कि इसमें किसे हाथ लगाना है और किसे नहीं ताकि किसी राजनैतिक गलती से बचा जा सके. पर उन्होंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की.

अधिकार की लड़ाई

● केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहकर्मियों के बीच आपसी नोकझोंक कोई नई बात नहीं है. पंडित नेहरू के जमाने से यह परंपरा चली आ रही है. अब मंत्रियों की आपसी लड़ाई के नए योद्धा हैं वाणिज्यमंत्री दिनेश सिंह और उनके ही मंत्रालय के राज्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी. दिनेश सिंह के मंत्रालय की बागडोर संभालने से पहले तक अहम पदों पर नियुक्तियां करने में दासमुंशी की काफी चलती थी. पर दिनेश सिंह आए तो वे अपना सिक्का चलाने की कोशिश करने लगे. अब वे चाहते हैं कि नियुक्तियां उनके लोगों की हों. दासमुंशी भी ऐसा ही चाहते हैं. इस लड़ाई के नतीजे राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम में दिखने लगे हैं. 8000 करोड़ रु. का सालाना धंधा करने वाले ये दोनों निगम सरकारी और राजनैतिक संरक्षण के खास

आधार माने जाते हैं.

पर तीन महीने से दोनों बिना अध्यक्ष के चल रहे हैं क्योंकि इनके लिए कई दावेदार मैदान में हैं. पिछले दो महीने में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने इन पदों के लिए कई काबिल लोगों के नाम सुझाए लेकिन राजनैतिक खींचतान के चलते अभी कोई भी नाम स्वीकृत नहीं हुआ है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

ख़ुश होते . . . मौज मस्ती करते बच्चों को देखना आपको ख़ुश करने के लिए काफ़ी है. बच्चों के लिए जितने ज़रूरी हैं खाना-पीना और हवा उतनी ही ज़रूरी है हंसी-ख़ुशी . . . मौज-मस्ती. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती . . . यही मज़े. एकदम वैसी ही कॉमिक पत्रिका जो हर बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है. आख़िर डिस्नी गैंग के सदस्य दुनिया भर के अरबों बच्चों के चहेते हैं . . . मनपसंद हैं.

बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को ख़ुश कर दीजिए.

यही है अद्‌भुत तरीका बच्चों को यह जताने का कि वे आपकी ज़िंदगी में सदा-सदा सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे. सबसे बढ़िया बात यह कि घर भर में गूंज उठे आपकी चहेती आवाज़.

आपके बच्चे की खिलखिलाहट.

आज ही सबस्क्रिपशन भेजिए
और आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें :
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि०
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न. 69 दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

LM COMICS

डिस्नी टुडे

अब उपलब्ध हर पखवाड़े
हिंदी और अंग्रेज़ी में.

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा
☐ सालाना: रु. 78/- ☐ छह महीने का: रु. 40/- हिन्दी
प्रति के लिए सबस्क्रिपशन. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नं _____ द्वारा कर रहा हूँ.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय: _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

114

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• मैं मरते दम तक अखबारों के सचाई प्रकाशित करने के अधिकार की रक्षा करूंगा.
■ **पी. चिदंबरम,** लोकसभा में मानहानि विधेयक की वकालत करते हुए, *राजस्थान पत्रिका*

• यह (मानहानि विधेयक) कानूनी आतंकवाद है.
■ **एच.एन. नंजेगौडा** (इंका सांसद), *हिंदुस्तान*

• राजीव गांधी को एक दिन के लिए मुझे सौंप दीजिए और मैं उनके दस्तखत का बयान ला दूंगा कि उन्होंने अपनी मां की हत्या की है.
■ **संजय सिंह,** *संडे*

• मैं भूखों नहीं मरना चाहता. मैं भी साधनसंपन्न होना चाहता हूं.
■ **संपत सिंह** (गृहमंत्री, हरियाणा), *रविवार*

• जनमोर्चा के नेताओं के लिए संसद की सीट पकड़े रहना अंतरात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण है. वे समझते हैं कि भागते चोर की लंगोटी ही सही.
■ **गुलाम नबी आजाद,** *दिनमान*

• राजनैतिक दल अंडे नहीं हैं जिन्हें तोड़कर आमलेट बना दिया जाए.
■ **हेमवती नंदन बहुगुणा,** *जनसत्ता*

• संवेदनशील होकर आप राजनीति में कैसे टिक सकते हैं? यहां तो गैंडे जैसी मोटी चमड़ी चाहिए.
■ **सुब्रमण्यम स्वामी,** *इलस्ट्रेटेड वीकली*

• टीएनवी वाले अब कह रहे हैं कि वे भारत के नागरिक हैं. वे भला उग्रवादी कैसे हो सकते हैं?
■ **सुधीर रंजन मजूमदार** (मुख्यमंत्री, त्रिपुरा), *संडे मेल*

• मैं तो नरेंद्र हीरवानी की कप्तानी में भी खेलने को तैयार हूं. मेरा अहं आड़े नहीं आता. मैं तो बस अपने देश की खातिर खेलता हूं.
■ **कपिलदेव,** *स्पोर्ट्सवीक ऐंड लाइफस्टाइल*

• मुझे रेलवे से अच्छा वेतन मिलता है तो मैं राष्ट्रीय टीम के बजाय रेलवे के लिए क्यों न खेलूं.
■ **मोहम्मद शाहिद,** *स्वतंत्र भारत*

• मेरी फिल्में भले पिटती हों, मैं नहीं पिटता. मैं कभी नहीं पिटूंगा.
■ **राज कुमार,** *स्टारडस्ट*

• माफ कीजिए साहब, मैं श्याम बेनेगल और गोविंद निहलाणी की 'सो कॉल्ड' आर्ट फिल्मों से जरा दूर ही रहना चाहता हूं जिन्हें लोग देखते नहीं.
■ **रजा मुराद,** *धर्मयुग*

आपकी चहेती पत्रिका
आपके दरवाज़े पर
न खरीदने का झंझट...
न खत्म होने का डर

इस सुविधा का लाभ उठाइए.
आपनी चहेती इंडिया टुडे
घर बैठे – नियमित पाइए.
न खरीदने जाने की ज़रूरत...
न अंक खत्म होने का डर,
इंडिया टुडे
समय से पहुंच जाए आपके घर !
बस कूपन भर कर भेज दीजिए,
देर मत कीजिए !

नाम :
डाक पता :

मूल्य : वार्षिक रु. 120/-
भुगतान का माध्यम – चैक/मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट
कृपया चैक निम्नलिखित नाम पर बनाएं और इस पते पर भेजें
लिविंग मीडिया इंडिया (प्र.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट थौमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. नं. 69, दिल्ली मथुरा रोड,
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

MILESTONES/IT/120

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चूहे की खुराफात

■ देश भर में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां बिजली विभाग फायदे में चलता हो. इनमें हर साल करोड़ों रुपए के घाटे का एक बड़ा कारण कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी होता है.

सभी कार्टून: मंजुला पद्मनाभन

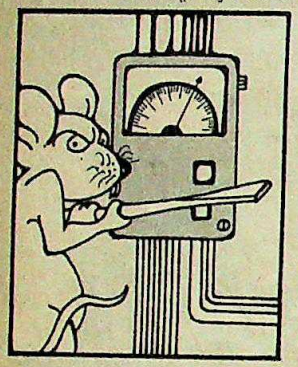

ऊपर से देखने में भले ही यह लगे कि दोषी उपभोक्ताओं को पकड़ कर घाटे पर अंकुश लगाया जाना चाहिए पर असल में यह काम कितना मुश्किल है इसका अंदाजा पिछले दिनों दिल्ली विद्युत प्रदाय के अनुभव से लगाया जा सकता है.

विभाग के कर्मचारियों ने एक फैक्टरी के मालिकों पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाकर उन्हें अदालत में पेश किया. आरोप पत्र में कहा गया था कि फैक्टरी के बिजली मीटर की सील टूटी हुई पाई गई. जवाब में खुद को बेकसूर बताते हुए फैक्टरी मालिकों ने दलील दी कि यह काम उन्होंने नहीं बल्कि एक चूहे ने किया है. जज साहब ने जब चूहे के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि वह तो शार्ट सर्किट की वजह से स्वर्ग सिधार चुका है. डेसू के अधिकारी अभी चूहे की शक्ल में आए इस सदमे से मुक्त भी नहीं हो पाए थे कि अभियुक्तों ने एक शगूफा छोड़ कर उन्हें चित कर दिया. बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि बिजली ऐसा सामान नहीं है जिसे चल संपत्ति की तरह उठा कर कोई चलता बने. लिहाजा अपराध संहिता की धारा 379 के तहत उन पर चोरी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

इश्क में अंधे

■ कहा जाता है कि प्रेमी दिलों के बीच जालिम दुनिया अक्सर दीवार बनकर खड़ी हो जाती है. लेकिन यह एक ऐसा किस्सा है जिसमें प्रेमियों के बीच एक कुत्ता दीवार बनकर खड़ा हो गया. कानपुर की एक अदालत में इन दिनों एक ऐसा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें प्यार की तान में अपनी बेसुरी आवाज ठूसने वाले एक कुत्ते को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. एक कुत्ता प्रेमी ने पुलिस में रपट दर्ज कराई कि उसके प्यारे कुत्ते को एक व्यक्ति ने महज इस अपराध के लिए मार डाला कि वह उस पर ठीक उस समय भौंकता था जब वह रात में अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था.

अखबारों के अनुसार खबर मिलने पर पुलिस ने कुत्ते की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे वहां पशु अस्पताल में भिजवा दिया गया. अस्पताल पहुंचने पर पुलिस के सिपाही ने पाया कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय किसी जरूरी मीटिंग में गए हुए हैं. सिपाही ने कुत्ते की लाश को अस्पताल में छोड़ा और अधीक्षक को बुलाने चला गया. लौटने पर उसने पाया कि लाश गायब थी. पुलिस ने नए सिरे से खोज अभियान चलाया और कुछ दिनों में ही लाश को

स्थानीय नदी में ढूंढ़ निकाला. अंतिम खबर आने तक कुत्ते के मालिक और बचाव पक्ष के वकील बेसब्री से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में थे ताकि न्याय के लिए जंग का अगला दौर शुरू हो.

रामायण बनाम क्रिकेट

■ हिंदुस्तानी खेल प्रेमियों में क्रिकेट की लोकप्रियता बुखार की हद तक पहुंच चुकी है. लोकप्रियता की यह मिसाल अकेली ही रह गई होती अगर टीवी के परदे पर रामायण का अवतार न हुआ

होता. सागर साहब की रामायण ने ऐसा समां बांधा कि देश भर के दर्शक उसके भक्ति सागर में डुबकियां खाने लगे. दोनों खेलों की लोकप्रियता अपने-अपने बाड़ों में फलती-फूलती रहती पर पिछले दिनों विधि ने कुछ ऐसा विधान रचा कि क्रिकेट प्रेमियों और रामायण प्रेमियों के बीच विकेट और तीर-कमान तन जाने की नौबत आ खड़ी हुई.

दोनों ओर के श्रद्धालुओं के बीच महाभारत छिड़ने की यह नौबत तब आ खड़ी हुई जब रामायण प्रेमियों ने जोधपुर के बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम में रामायण समारोह करने की घोषणा कर डाली. क्रिकेट प्रेमियों के मन में यह खबर बाउंसर की तरह लगी. उन्हें लगा कि इस समारोह से उनकी प्यारी पिच बरबाद हो जाएगी और उनके स्टंप हमेशा के लिए उखड़ जाएंगे. लिहाजा इधर समारोह का विरोध शुरू हुआ और उधर रामायण प्रेमियों ने अपने धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए तरकस से तीर निकाल लिए. शहर के नेताओं से लेकर पत्रकारों के भी गुट बन गए. बात आमरण अनशन और जवाबी अनशन की धमकियों तक जा पहुंची. सुना है मामले को अब अदालत के दरवाजे तक ले जाने की बात चल रही है.

लुट गए लुटेरे

■ इधर पिछले कुछ बरसों से बैंकों के लुटने का ऐसा फैशन चल निकला है कि लुटेरों की नजर से बचे रहने वाले बैंकों को जल्दी ही अपने बैंक होने पर शर्म आने लगेगी. सच तो यह है कि जिस बैंक से जितना अधिक पैसा लूटा जाता है उसकी साख उतनी ही बढ़ जाती है. मगर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में दो लुटेरों ने जिस बहादुरी के साथ एक बैंक के हाथों लुटने का उदाहरण पेश किया उसने लुटेरों की पूरी बिरादरी की साख को मिट्टी में मिला दिया है.

हुआ यह कि धामपुर कस्बे में दो जवान लुटेरे चेहरे पर नकाब पहन कर और हाथों में देसी तमंचे लहराते हुए फुर्ती के साथ एक बैंक में दाखिल हुए. अंदर घुसते ही उन्होंने बैंक के मैनेजर से तिजोरी खोलकर माल उनके हवाले करने का हुक्म दिया. बेचारा मैनेजर पहले तो कुछ देर के लिए सकपकाया पर फिर साहस बटोरकर जब उसने लुटेरों को यह बताया कि वे गलती से नेत्र बैंक में घुस आए हैं तो बेचारों को ऐसा सदमा पहुंचा कि वे तमंचे वहीं छोड़ बाहर भाग लिए. लेकिन मैनेजर ने कुछ लोगों की सहायता से उन्हें धर दबोचा. लुटेरों ने काफी हाथ-पांव जोड़े पर मैनेजर ने उन्हें नेत्रदान के बारे में लंबा भाषण पिलाने के बाद तब छोड़ा जब वे खुद नेत्रदान के

लिए राजी हो गए. जाते-जाते उन्होंने न केवल अपनी मृत्यु के बाद आंखें दान करने के फार्म पर हस्ताक्षर किए बल्कि जिंदगी में फिर डकैती न करने की भी कसम खाई.

—संकलन: विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

TVs Radios 2-in-1s Calculators Projectors Digital Watches

KELTRON

RELYTRONICS

No better guarantee

रिलायट्रॉनिक्स.

अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके साथ विश्वसनीयता जुड़ी है.

वैसे हमारे लिए विश्वसनीयता महज एक शब्द ही नहीं बल्कि पिछले बीस सालों में विस्तृत श्रृंखला के औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों के निर्माण में हासिल किये गये हमारे अनुभव और तकनीकी कुशलता का प्रतीक है.

इन उत्पादनों में टी.वी., रेडियो, टू-इन-वन, कैलकुलेटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के अलावा संचार, देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किये जानेवाले इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम भी शामिल हैं. और तो और, हम इन उत्पादनों में इस्तेमाल होनेवाले कलपुर्जे, जैसे कैपेसिटर्स, डायोड्स, रेसिस्टर्स, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स वगैरह भी बनाते हैं.

यही नहीं, कई नामी कंपनियां भी अपने उत्पादनों के निर्माण के लिए हमारे ये कलपुर्जे खरीदती हैं.

केल्ट्रॉन रिलायट्रॉनिक्स : इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वसनीयता के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं.

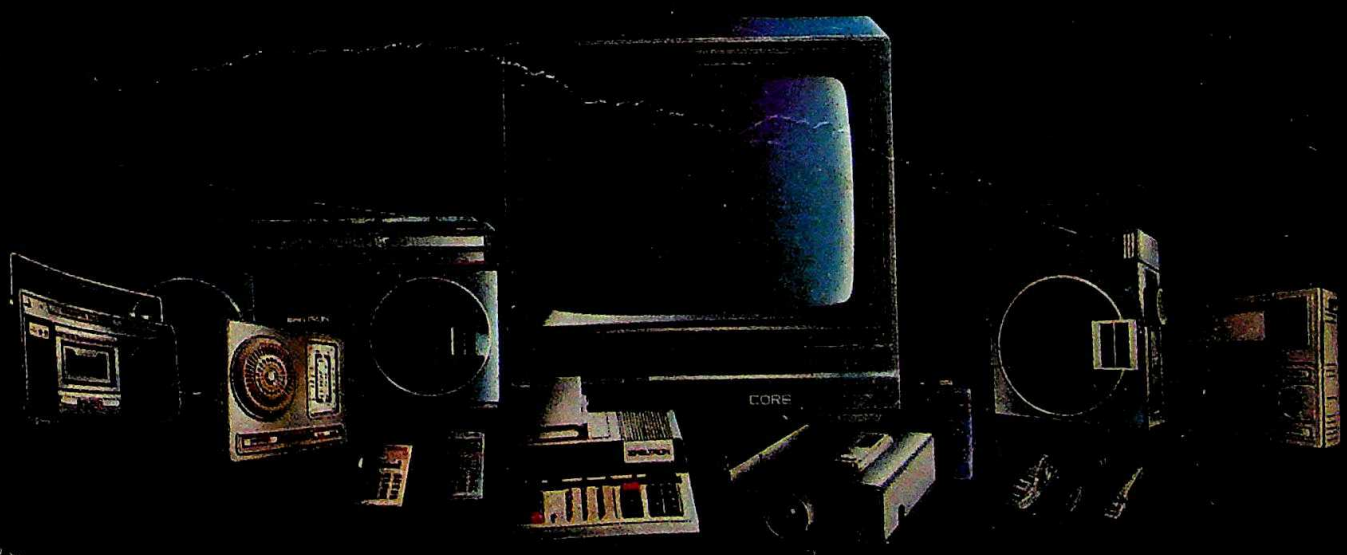

केल्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ; कॉर्पोरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, (कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स), शस्थमगलम, त्रिवेन्दम ६९५ ०१० फोन ६९१०६ शाखा व प्रादेशिक कार्यालय अहमदाबाद बैंगलोर भोपाल बम्बई कलकत्ता कालीकट कोचीन गवाहाटी हैदराबाद मद्रास मदराई नयी दिल्ली, पटना, त्रिवेन्दम और विशाखापटणम्

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मैसूर दशहरा

मैसूर तशरीफ लाइये!
दस दिन सुबह-शाम. संगीत, नृत्य और शानदार समारोहों की धूमधाम.

मंदिरों, महलों और सम्पन्न सांस्कृतिक परम्पराओं वाले मैसूर के दशहरे से बढ़कर दशहरा और कहां का!

भव्य जलूस देखने के बाद, रोशनी की चकाचौंध से जगमगाते महल को निहारने के उपरांत, चंदन और सिल्क खरीदकर, चिड़ियाघर के मज़े लेकर, नाचता-गाता वृंदावन मन भर देखकर, थकियेगा मत! अभी बहुत कुछ है!

मैसूर का माहोल. आमोद-प्रमोद से भरपूर.

यहां से सिर्फ 16 किमी दूर टीपू सुलतान की ऐतिहासिक राजधानी — श्रीरंगपट्ना. पत्थर के किले जिन्होंने अपनी आंखों से देखा बहादुरी का दंग करने वाला वह जंग!

मैसूर से सिर्फ 30 किमी — सोमनाथपुर. पत्थरों का चमत्कार. याद आयेगा बार-बार.

पक्षियों का नज़ारा? रंगनथिट्टु पक्षी विहार, भूले नहीं भूलेगा. हाथी की सवारी करना चाहते हैं? बाघ और शेर का सामना करना चाहते है, तो आइये, बंदीपुर, काबिनी नदी के तट पर स्थित जँगल "लौज" या नागरहोले चलें.

अपनी छुट्टियां आराम से बिताइये. केएसटीडीसी के किसी भी होटल में आरक्षण कराइये. केएसटीडीसी के कनेक्टेड टूर का फायदा उठाइये. मैसूर जरूर आइये! और हाँ, कैमरा लाना मत भूल आइयेगा।

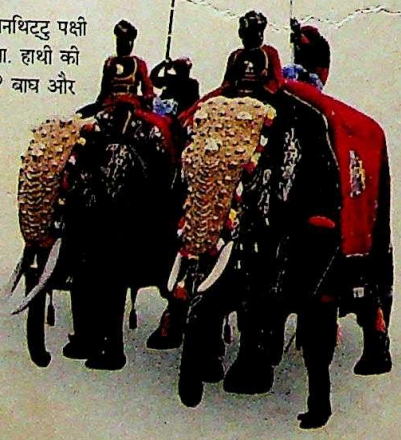

और सूचना के लिये सम्पर्क कीजिये:

कर्नाटक टूरिज्म
64, सेंट मार्क्स रोड
बेंगलोर-560 001 फोन: 579139

MYSORE DASARA

सिन्टेक्स - वक्त की कसौटी पर अव्वल, एकमात्र विश्वसनीय रेडीमेड पानी की टंकिया

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिन्टेक्स ने एक दशक से भी ज्यादा समय से सभी तरह की आबोहवाओं का सामना करके अपनी गुणवत्ता को साबित कर दिखलाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक, पानी के संग्रह एवं परिवहन के सभी उपयोगोंमें चल रही, लाखों सिन्टेक्स की टंकिया, अब दिन ब दिन और भी लोकप्रिय होती जा रही है !

कम्प्यूटर की सहायता से चलने वाले आधुनिक मशीनों पर अनोखे मोल्डींग प्रोसेस से बनी –सिन्टेक्स पानी की टंकियों के लाभ भी अद्वितीय है।

* वजन में हल्की * लगाने में आसान * मजबूत एवं टिकाऊ * देखभाल से मुक्त * १०० % लीकप्रूफ एवं रस्टप्रूफ * बहुत ही आरोग्यप्रद * १०० लिटर से २०,००० लिटर की विविध साईजो एवं आकारों में उपलब्ध * बिक्री उपरांत सेवा भारत में सर्वत्र.

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :

सिन्टर प्लास्ट कंटेनर्स

प्लास्क्सि डिवीजन द भारत विजय मिल्स लि. कलोल (उ गुजरात) ३८२ ७२१
फोन: (०२७६४), २२२८, ३१४४, ३१४५ ग्राम: "SINTEX"
टेलेक्स: ०१२०५-२०२ SPC IN फॅक्स: (०२७६४) २४३६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सिन्टेक्स - दुनियाकी नं १ प्लास्टिक पानी की टंकिय

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Haridwar.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आशंकाएं और हताशा

आशंकाएं और उनसे उपजी हताशा जैसे हावी रही पूरे पखवाड़े पर. पंद्रह दिनों में ही जैसे पूरा माहौल बदल गया. तमंचे तनने लगे, तलवारों पर सान चढ़ने लगी. ऐसी आशंकाओं को सिर्फ मानहानि विधेयक जैसे मसले से बल नहीं मिलता, आहत मासूमियत का छद्म और खोखलापन भी उन्हें पुष्ट करता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या यों कहें सूचनाएं और खबरें देने की आजादी पर अंकुश लगाने जैसी अहम जिम्मेदारी कम-से-कम उन लोगों को तो नहीं ही सौंपी जा सकती है जो आज सत्ता में हैं.

आज हम जैसे अतीत-मोह के दौर से गुजर रहे हैं—पंडित नेहरू, डॉ. राधाकृष्णन और गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गजों के पुण्य स्मरण के दौर से. ऐसा शायद इसलिए कि आज के शासक उन लोगों की तुलना में बेहद बौने दिखते हैं. और तभी शायद मानहानि विधेयक का विरोध बेहद मुखर हो उठा है. इसका मतलब यह नहीं है कि यह विधेयक कोई कम निंदनीय है. हमारे लोकतंत्र में चाहे जितनी खामियां हों, देश को अगर किसी चीज पर नाज है तो यह लोकतंत्र ही है. इस लोकतंत्र को उन लोगों ने जीवन दिया है, उसे मजबूत किया है जो लोग हमारे इतिहास के पन्नों को सुशोभित कर रहे हैं.

रेखाचित्र
पिअली दत्त गुप्ता

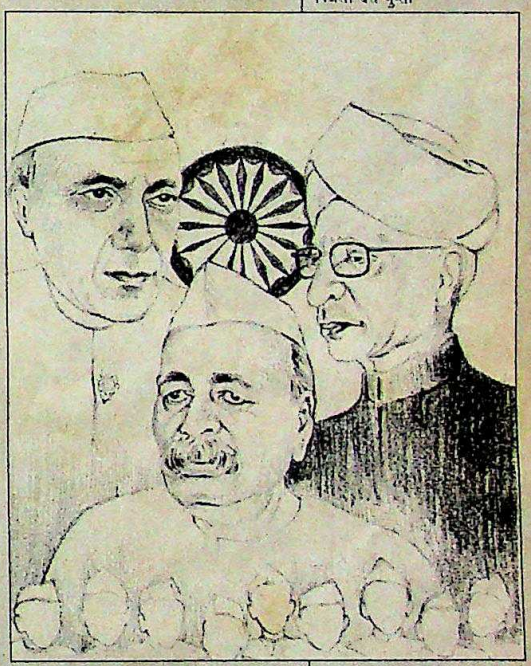

लेकिन आज हम जैसे एक क्रूर विडंबना से जूझ रहे हैं. आज कोई भी ऐसा नेता नहीं है—न विपक्ष में, न सत्ता पक्ष में—जो इतिहास में स्थान पाने के योग्य भी हों. लोकतंत्र के मेरुदंड, संसद में एक राज्य के प्रति केंद्र के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर हंगामा और हिंसा की वारदातें हो जाती हैं. सत्ता पक्ष के अगुआ तक इस शर्मनाक 'तमाशे' को रोकते नहीं बल्कि उकसाते दिखते हैं.

दूसरे दिन इस राज्य—आंध्र प्रदेश—के 162 विधायकों पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनकी पिटाई की जाती है महज इसलिए कि उन लोगों ने प्रधानमंत्री निवास तक मार्च करने की हिमाकत की थी. और, दूसरे राज्य में असंतुष्ट विधायक मंत्री बनाए जाने की मांग करते हुए सरकार को गिराने तक की धमकी दे डालते हैं. मिजोरम के ये विधायक इतने दुस्साहसी हैं कि अपने लिए 'कमाऊ' मंत्रालयों के नाम तक सुझाने से नहीं शरमाते.

लगभग यही कहानी इससे पहले नगालैंड में दोहराई जा चुकी थी. और अब ये दोनों राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन हैं. यानी ऐसे राज्य अब चार हो गए हैं.

इन तमाम बातों की एक ही वजह है—नेताओं का नैतिक पतन और दूषित राजनैतिक माहौल. संजय सिंह के खिलाफ चाहे जो भी सबूत हों, जनता को उनकी गिरफ्तारी के पीछे उनके व्यक्तिगत रिश्तों की नहीं राजनैतिक समीकरणों की भूमिका नजर आती है.

इन्हीं कारणों से मानहानि विधेयक बेहद खौफनाक दिखने लगता है. बेशक, भारतीय प्रेस में खामियां भी हैं. ऐसा नहीं है कि गैरजिम्मेदार पत्रकारिता न होती हो. उत्तेजना और सनसनी फैलाने की भी कोशिशें होती हैं. लेकिन ये न तो कोई नई बातें हैं और न ही केवल इसी देश में होती हैं. तमाम आजाद मुल्कों के अखबारनवीसों में ऐसे तत्व मौजूद हैं. यही लोकतंत्र का सार भी है और उसकी चुनौती भी.

तो फिर ऐसे भयावह विधेयक को इतनी बेशर्म जल्दबाजी से पारित कराने की क्या जरूरत आन पड़ी? सत्तासीनों के अपने तर्क हैं—कि जनता ने भारी बहुमत से जिताकर उन्हें सत्ता में बिठाया तो यह उनमें उसकी आस्था का ही परिचायक है.

किसी तथ्य की इससे ज्यादा तोड़मरोड़ नहीं की जा सकती. 1984 में जो सरकार चुनी गई थी और आज जो सरकार कुर्सी पर विद्यमान है, दोनों के प्रति जनता की भावनाओं में जमीन-आसमान का अंतर है. शासक दल अगर यह समझता है कि उसे आज भी '84 वाला जन समर्थन हासिल है तो वह मुगालते में है.

—दिलीप बॉब

1984 में जो सरकार चुनी गई थी और आज जो सरकार कुर्सी पर विद्यमान है, दोनों के प्रति जनता की भावनाओं में जमीन-आसमान का अंतर है

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या यों कहें सूचनाएं और खबरें देने की आजादी पर अंकुश लगाने जैसी अहम जिम्मेदारी कम-से-कम उन लोगों को तो नहीं ही सौंपी जा सकती है जो आज सत्ता में हैं

आज हम पंडित नेहरू, डॉ. राधाकृष्णन और गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गजों की याद कर रहे हैं तो शायद इसलिए कि आज के शासक उन लोगों की तुलना में बेहद बौने दिखते हैं. तभी शायद मानहानि विधेयक का विरोध मुखर हो उठा है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भवान सिंह

दिल्ली में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन : अपूर्व एकजुटता

मानहानि विधेयक

चौथे खंभे पर चोट

राष्ट्रव्यापी विरोध के कारण सत्तारूढ़ दल के हाथों से तोते उड़ गए

अपनी गिरती साख और घोटालों के लगातार भंडाफोड़ों से परेशान केंद्र सरकार ने पिछले पखवाड़े समाचार जगत का मुंह बंद करने के लिए बहुत फूहड़ रास्ता अपनाया. उसे सफलता तो नहीं मिली बल्कि जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और बदनामी से बचने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ी. पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला **और वरिष्ठ संवाददाता** पंकज पचौरी **की रिपोर्ट:**

जो तलवार उठाते हैं, उन्हें तलवार से मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए"—ये शब्द केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम ने पिछले पखवाड़े संसद में कहे. उनके मुंह से ये शब्द तब फूटे जब उन्होंने राजीव गांधी सरकार का ताजा विध्वंसकारी हथियार —मानहानि विधेयक पेश किया.

लेकिन दो दिन में ही सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही जाल में उलझ गई. विधेयक का निशाना बने अखबारों ने इसका अभूतपूर्व विरोध किया. सरकार को झुकना पड़ा और विधेयक पर राज्यसभा में विचार रोकना पड़ा.

लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था. समाचार माध्यमों से लेकर संविधान विशेषज्ञों, वकीलों से लेकर आम आदमी और विपक्ष से लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की जबरदस्त प्रतिक्रिया से साबित हो गया कि दरअसल इस विधेयक का मकसद क्या है.

विधेयक अशोभनीय जल्दबाजी के साथ लोकसभा में पेश किया गया. इंका सांसदों को एक विशेष व्हिप के जरिये साफ बता दिया गया था कि दो पेजी विधेयक पास हो ही जाना चाहिए. आखिरकार नौ घंटे की हंगामाखेज बहस के बाद विधेयक पास हो गया जबकि 59वें संविधान संशोधन जैसे इसी तरह के राष्ट्रीय महत्व के विधेयक पर संसद में एक हफ्ते तक बहस हुई थी.

लेकिन जब विधेयक का विरोध राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया तो स्पष्ट हो गया कि गलत सलाह पर उठाया गया यह कदम राजीव गांधी के 43 महीनों के राज में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला है. उन्हें विधेयक को राज्यसभा में पेश न करने की अनोखी घोषणा तो करनी ही पड़ी, बदनामी से बचने के लिए यह भी कहना पड़ा कि वे प्रेस की आजादी के लिए वचनबद्ध हैं.

अगर सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को अंतिम क्षण तक गुप्त न रखा होता तो ऐसा कुछ भी न होता. लोकसभा के स्थगन के ठीक दो दिन पहले जब इस विधेयक को सदन में पेश किया गया तो सत्तारूढ़ पार्टी से सहानुभूति रखने वाले पत्रकारों को भी भारी ताज्जुब हुआ.

विपक्षी सांसदों को विधेयक की जांच-पड़ताल करने का बिलकुल समय ही नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिला. विधेयक पारित होने के वक्त विपक्ष का जबरदस्त विरोध और लोकसभा से बहिर्गमन आने वाले तूफान की स्पष्ट चेतावनी थी. फिर भी सरकार इस तथ्य को नकारते हुए आगे बढ़ती गई कि विधेयक से भारतीय लोकतंत्र की जड़ों पर ही प्रहार होगा. विधेयक में दूसरी बातों के अलावा यह भी प्रावधान है कि 'मानहानि वाली बातें' लिखने वाले पत्रकारों के मुकदमे की दैनंदिन सुनवाई होगी और उन्हें न्यूनतम सजा दिलेगी. इतना ही नहीं, सबूत जुटाने का भार भी अभियुक्त यानी पत्रकार पर रहेगा.

लेकिन सरकार को असली धक्का उस वक्त लगा जब समूचा समाचार जगत एकता का दुर्लभ उदाहरण पेश करते हुए विधेयक के खिलाफ लड़ाई में उतर पड़ा. इस लड़ाई की अगुआई वरिष्ठ पत्रकार चो. रामास्वामी ने की. उन्होंने मद्रास से हर बड़े संपादक को फोन करके सीधी लड़ाई के लिए राजी किया. नतीजे में 24 घंटे के भीतर 30 संपादक रणनीति तय करने के लिए दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिले. इसके पहले ही विभिन्न पत्रकार संगठनों ने हर संभव साधनों से विधेयक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान कर दिया.

विरोध के शुरुआती सुरों में जब कई सुर आन मिले तो बुजुर्ग नेता कमलापति त्रिपाठी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और प्रमुख संसद सदस्यों—चिमनभाई मेहता और एच.एन. नंजेगौडा समेत सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद और नेता भी खुलेआम विधेयक की मुखालफत में उतर आए. त्रिपाठी की टिप्पणी थी, "मेरे विचार से विधेयक वापस ले लिया जाना चाहिए."

जब प्रधानमंत्री ने देखा कि भारी मुसीबत पैदा होने वाली है तो उन्होंने तमिलनाडु का दौरा रद्द कर दिया और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी सहयोगियों को विचार-विमर्श के लिए बुला लिया. उनके ज्यादातर सहयोगियों ने उन्हें राय दी कि सरकार विधेयक पर नरम रवैया अपनाए.

प्रधानमंत्री ने रुख नरम करने का संकेत देने के लिए सामान्य संसदीय प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए संसद के बजाय पार्टी मंच से घोषणा की कि सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पर बहस टालने का फैसला किया है. एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में इंका प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने घोषणा की, "हम विधेयक पर बहस

पुराने कानून और नए कानून में अंतर

पुराना कानून

मानहानि साबित करने की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर.

मानहानि के मामलों की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में.

मामले के निबटारे की कोई समय-सीमा नहीं.

न्यूनतम कारावास नहीं.

'घोर अशोभनीय,' 'फूहड़' और 'ब्लैकमेल के इरादे वाली' सामग्री कानून के दायरे में नहीं.

अपराध के इलजाम के लिए कोई दंड नहीं.

अपने को बेकसूर साबित करने के लिए दस आधार. इसमें अच्छे इरादे से सामग्री का प्रकाशन और तथ्यों तथा जनहित पर आधारित विचार शामिल हैं.

सरकारी विभागों के साथ दूसरों जैसा ही बरताव.

मुकदमे के पहले दंड नहीं.

अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से विशेष छूट.

संक्षिप्त सुनवाई का प्रावधान नहीं.

नया कानून

अपने को निर्दोष साबित करने का पूरा भार अभियुक्त (प्रकाशक) पर.

मामला सीधे सत्र अदालत में जाएगा.

फैसला 90 दिन के भीतर.

पहली बार अपराध के लिए न्यूनतम एक महीने की जेल, बाद में अपराधों के लिए कम से कम तीन महीने की जेल और जुर्माना.

'घोर अशोभनीय', 'फूहड़' और 'ब्लैकमेल के इरादे वाली' सामग्री की खास परिभाषा नहीं. लिहाजा इन शब्दों का अर्थ तोड़ना-मरोड़ना संभव.

अपराध का इलजाम लगाना भी अपराध.

आपराधिक इलजाम के मामले में अपने को निर्दोष साबित करने का कोई आधार नहीं.

किसी व्यक्ति के खिलाफ लगे अपराध के आरोपों की सूचना प्रसारित करने वाले सरकारी अधिकारियों को विशेष छूट.

अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होने की छूट के लिए प्रत्युत्तर छापना जरूरी.

अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य.

संक्षिप्त सुनवाई का प्रावधान.

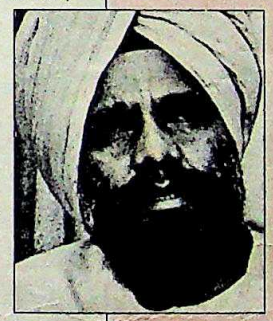

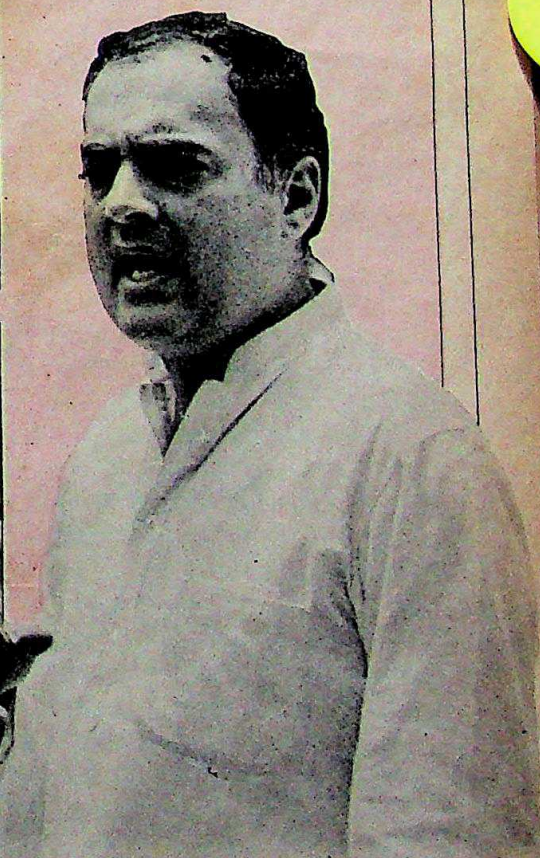

(ऊपर बाएं से दाएं) बूटा सिंह; चिदंबरम; (नीचे दाएं से बाएं) भगत; भारद्वाज: अनोखी सूझ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और चर्चा के लिए तैयार हैं. इस बारे में हमारी नीयत साफ है." उन्होंने विधेयक पर समाचार जगत से बातचीत करने और उपयुक्त सुझाव देने के लिए विदेशमंत्री पी.वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बनाने की भी घोषणा की. पर राजीव अभी भी अपने कड़े रवैये पर अड़े रहने का नाटक कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि विधेयक जरूरी है. मुझे खुद पक्का भरोसा है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं."

प्रधानमंत्री ने समाचार जगत पर यह आरोप भी लगा दिया कि विधेयक को बिना पढ़े ही वह हो-हल्ला मचा रहा है. पता नहीं उन्होंने ऐसा किस बिना पर कह दिया जाने वाले संपादक भी जुलूस में पहुंचे.

तब तक आम जनता भी समझ चुकी थी कि विधेयक खतरनाक भले ही न हो लेकिन समाचार जगत को प्रधानमंत्री के नजदीकी लोगों के घोटाले का और अधिक पर्दाफाश करने से रोकने की एक फूहड़ कोशिश जरूर है. (बंबई के एक अखबार के लिए पांच प्रमुख महानगरों में कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 70 फीसदी लोगों का मानना था कि विधेयक वापस ले लिया जाना चाहिए.) इंका सांसद नंजेगौडा ने कहा, "70 करोड़ की आबादी में से शायद 70 लोगों को प्रभावित करने वाले विधेयक को उचित कैसे कहा जा सकता है?" चिमनभाई मेहता का कहना था, "यह वही समाचार जगत है जिसने 1971, 1980 और 1985 में इंका की मदद की थी."

भवान सिंह

क्योंकि ज्यादातर अखबारों ने अपने संपादकीयों और पहले पेज पर छपे आलेखों में विधेयक के एक-एक प्रावधान का विश्लेषण किया है.

आंशिक सफलता मिलने के बाद समाचार जगत ने ठान लिया कि जब तक विधेयक वापस नहीं हो जाता लड़ाई जारी रहेगी. समाचार जगत के संगठनों ने बातचीत की सरकार की पेशकश ठुकरा दी और दिल्ली में इंडिया गेट से बोट क्लब तक जोशीला जुलूस निकाला. इसमें प्रमुख संपादक तो शामिल हुए ही, 'द स्टेट्समैन' के सी.आर. ईरानी, ईनाडु समूह के रामोजी राव और 'इंडियन एक्सप्रेस' के रामनाथ गोयनका जैसे अखबारों के मालिकों ने भी भाग लिया. 'द टेलीग्राफ' के एम.जे. अकबर और 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के गिरिलाल जैन जैसे सरकार समर्थक समझे

राजघाट पर विपक्ष का जुलूस: विरोध का तूफान

अब जबकि तूफान थोड़ा-बहुत थम गया है, इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि आखिर सरकार का इरादा क्या है और उसने राजनैतिक हाराकिरी जैसा यह विधेयक पेश करने और उसे पास कराने के लिए यही वक्त क्यों चुना. सूत्रों के मुताबिक, यह प्रक्रिया 1987 के आरंभ में उस समय गुप्त रूप से शुरू हुई जब केंद्रीय गृह मंत्रालय को दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों का अचानक ध्यान हो आया. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दरअसल बच्चन की गतिविधियों, बोफोर्स तथा एचडी-डब्ल्यू सौदों का भंडाफोड़ होने के बाद विधेयक पर तेजी से काम होने लगा.

गृहमंत्री ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए बदनामी विधेयक पर एक 20 पेजी नीति पत्र तैयार कर डाला. पहले इसे जांच-पड़ताल के लिए मंत्रिमंडल के पास और फिर विधेयक तैयार करने के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजने की बजाय सीधे सरकार की विधायी शाखा के पास भेज दिया गया. 1987 के मध्य में जब रक्षा घोटालों का मामला बेहद गर्म था, गृह मंत्रालय यह विधेयक मंजूर कराने के लिए मंत्रिमंडल के सामने ले गया.

मंत्रिमंडल ने गृहमंत्री बूटा सिंह के नेतृत्व में आठ मंत्रियों की एक समिति बनाई. इस समिति में पी. शिवशंकर, वसंत साठे, हरकिशनलाल भगत, चिदंबरम और हंसराज भारद्वाज भी थे. विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए इसकी कम-से-कम 20 बैठकें हुईं. और जब इस जनवरी में मंत्रिमंडल की राजनैतिक मामलों की समिति के सामने यह विधेयक पहुंचा तो प्रधानमंत्री और बूटा सिंह, चिदंबरम, भगत, भारद्वाज तथा शिवशंकर जैसे उनके विश्वसनीय मंत्री उसके पक्ष में बोले. पेशे से अधिवक्ता चिदंबरम और भारद्वाज ने विधेयक को अंतिम रूप दिया. हालांकि कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने विधेयक की राजनैतिक जटिलताओं के बारे में चेतावनी दी लेकिन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जब विधेयक को तीसरी बार चर्चा के लिए लाया गया तो मंत्रिमंडल ने उसे मंजूरी दे दी.

कुछ लोगों को संदेह है कि राजीव के प्रमुख सहयोगी सतीश शर्मा के घनिष्ठ मित्र ललित सूरी से संबंधित घोटाले का पर्दाफाश होने के कारण इस विधेयक को लाने में इतनी जल्दी की गई. राजीव गांधी की लोकप्रियता तेजी से घटने के संकेत मिल रहे थे. आगे बदनामी से बचने की कोशिश में राजीव गांधी और उनके सलाहकारों ने यह हिसाब-किताब लगाया ही नहीं कि समूचा समाचार जगत एकजुट हो जाएगा.

अब सवाल यह है कि क्या सरकार चुपचाप विधेयक को खत्म हो जाने देगी या हर किसी को दुविधा में रखेगी. मौजूदा संकेतों से तो यही दिखता है कि सरकार की रणनीति विधेयक को दुधारी तलवार की तरह समाचार जगत के सिर पर लटकाए रखने की है ताकि आगे कोई भी भंडाफोड़ बहुत सोच-विचारकर किया जाए. लेकिन समाचार जगत इस तरह झुकने के मूड में नहीं है इसलिए यह तलवार उसी व्यक्ति के सिर पर लटक सकती है जिसे कि विधेयक में बचाने की पुरजोर कोशिश की गई है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मानहानि विधेयक

अलोकतांत्रिक प्रक्रिया

मानहानि विधेयक तो कानून बनाने की समूची प्रक्रिया में मूल त्रुटि का ही इजहार है. पिछले कुछ समय से सरकार इसी प्रक्रिया पर अमल करती आ रही है. ऐसे कई मौके आए हैं जब अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में विधेयक रख दिए जाते हैं पर उनसे संबद्ध या प्रभावित होने वाले लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता.

जब कोई विधेयक तैयार किया जाता है तो उसे उससे प्रभावित होने वाले लोगों और संगठनों के बीच जारी किया जाना चाहिए. उनके सुझावों और टिप्पणियों पर गौर करने के बाद सरकार को उसे संसद में पेश करना चाहिए. दुर्भाग्य से हमारे यहां यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती. इसका एक और उदाहरण है आयकर संशोधन विधेयक जिसमें 150 धाराएं हैं. इसके कुछ प्रावधान तो बहुत ही कठोर हैं. उन पर जैसे कोई सोच-विचार ही नहीं किया गया है. अब आया है यह मानहानि विधेयक जिसमें अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर रोक लगाने वाले कई आपत्तिजनक प्रावधान हैं जो प्रेस की आजादी को भी प्रभावित करेंगे. हैरानी है कि इसे पत्रकारों, वकीलों, न्यायविदों और सार्वजनिक जीवन के प्रमुख लोगों के बीच बांटने के पहले ही संसद में पेश कर दिया गया.

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट और दूसरे प्रेस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के लिए यह कदम उठाना जरूरी था. लेकिन विधि आयोग की रिपोर्ट 10 वर्ष पहले और दूसरे प्रेस आयोग की रिपोर्ट चार वर्ष पहले पेश की गई थी. ऐसे में इन रिपोर्टों पर इतनी उतावली में कदम उठाने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? और फिर, इनमें से किसी भी रिपोर्ट में वैसे कठोर प्रावधान नहीं सुझाए गए हैं जो इस विधेयक के 13वें से लेकर 15वें अनुच्छेद में दिए गए हैं.

मानहानि विधेयक को लेकर जितनी नाराजगी है और इसका जिस कदर विरोध हो रहा है, उतना आजाद भारत में किसी और विधेयक या कानून को लेकर नहीं हुआ. और ऐसा बेवजह नहीं है. विधेयक के कुछ प्रावधान आगे प्रेस की आजादी में निश्चित रूप से बाधक बनेंगे. प्रेस वाद-विवाद का राजनैतिक आधार मुहैया करके लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

> "प्रेस की आजादी में शासक वर्ग को नाराज करने, झिंझोड़ने या उसकी नींद हराम करने वाली खबरें देने की आजादी भी शामिल है.... कुशासन खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार भंडाफोड़ ही है"

इसकी संस्थागत जरूरतों की हिफाजत की ही जानी चाहिए. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की जो आजादी दी गई है, उसमें प्रेस की आजादी भी शामिल है. बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ शासक वर्ग या आबादी के किसी वर्ग को अच्छी लगने वाली खबरें या विचार देने तक ही सीमित नहीं है. इसमें उस जमात को नाराज करने, झिंझोड़ने या उसकी नींद हराम करने वाली खबरें या विचार देने की आजादी भी शामिल है.

खबरें हासिल करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का एक मूलभूत तत्व है. अगर खबरों और खासकर सरकारी खबरों तक प्रेस की पहुंच न हो तो प्रेस की आजादी का कोई मतलब नहीं. जब तक लोगों को खबरें जानने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल कैसे किया जा सकता है?

यहां महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं: क्या सरकार के अंदरूनी कामकाज की जानकारी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? अगर शासक ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो क्या लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए? और अगर इसके उलट हो रहा हो तो क्या उनके कामों का भंडाफोड़ नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र के शासकों के सत्ता दुरुपयोग, मनमानी, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और दूसरे गलत कामों का भंडाफोड़ चौथा स्तंभ करता है. वही लोगों के हितों का पहरुआ होने के अलावा सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह भी बनाता है.

कुशासन खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार भंडाफोड़ ही है. लिहाजा ऐसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए जिससे प्रेस के इस महत्वपूर्ण काम-काज पर असर पड़े. इंग्लैंड की एक अदालत में बहुचर्चित 'स्पाई कैचर केस' में कहा गया था, "सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करने में प्रेस की विधिसम्मत भूमिका है. एक खुले लोकतांत्रिक समाज में ऐसा होना ही चाहिए." आजादी के महान प्रेमी थॉमस जेफरसन ने कहा था, "अगर मुझे यह फैसला करना हो कि हमें बिना अखबार की सरकार चाहिए या बिना सरकार का अखबार, तो मुझे दूसरा विकल्प चुनने में एक क्षण भी नहीं लगेगा."

जब भी इस अधिकार का गला घोंटा गया, लोकतंत्र की छायामात्र ही बची रह गई. ऐसे में सत्ता के इस्तेमाल पर जनमत का अंकुश खत्म हो जाता है. अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र भी तानाशाही में बदल जाएगा. लोकतंत्र की तंदुरुस्ती का सच्चा पैमाना प्रेस ही होता है. लोकतंत्र हो या तानाशाही, किसी भी सरकार के आचरण का आईना अखबार ही होते हैं. प्रेस पर किसी भी तरह का हमला और अभिव्यक्ति की उसकी आजादी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गला घोंटने की कोशिश का मतलब लोकतांत्रिक तौर-तरीकों को ताक पर रखना और तानाशाही की तरफ कदम उठाना है. मुझे यकीन है कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इसका समर्थन नहीं करेगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Foundation Original and eGangotri

आर के. गुप्ता

मोदी हत्याकांड

रिश्तों व राजनीति की गुत्थी

सीबीआई की ढीली-ढाली कहानी पर आम लोगों को संदेह

प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या के मामले में जनमोर्चा नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी ने भारी राजनैतिक बवंडर का रूप ले लिया है. संजय सिंह पर आरोप हैं कि उन्होंने मोदी की पत्नी अमिता के साथ विवाहेतर संबंधों के कारण मोदी की हत्या की साजिश की. लेकिन सीबीआई के दावों में कई पोल भी नजर आते हैं. प्रस्तुत है रिपोर्ट:

सीबीआई का जासूस (संजय सिंह की ओर इशारा करते हुए अमिता मोदी से पूछता है): क्या इन्हें आप जानती हैं?

अमिता: हां.

जासूस (संजय सिंह से): आप इन्हें जानते हैं?

संजय: हां. बहुत अच्छी तरह.

जासूस (अमिता से): इनसे आपके कैसे रिश्ते हैं?

अमिता: ये हमारे पारिवारिक मित्र हैं.

जासूस: आपके रिश्ते किस हद तक हैं?

अमिता: हद से आपका मतलब? हम घनिष्ठ मित्र हैं.

जासूस (अमिता से): ठीक है, आपके विवाहेतर शारीरिक संबंध पहली बार कब हुए?

अमिता एकदम सकते में आ जाती हैं लेकिन भावशून्य निगाहों से संजय की ओर ताकती हैं.

संजय (गुस्से में कुर्सी से उठते हैं): आप क्या बकवास कर रहे हैं? यह सवाल मुझसे पूछकर देखिए, मैं आपको कैसा करारा जवाब देता हूं. मुझसे यह भी पूछिए कि जब मैं राजीव का घनिष्ठ दोस्त था तब सोनिया गांधी से मेरे किस तरह के रिश्ते थे. (और भन्नाकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं).

जासूस (अमिता से): वे सिर्फ आपको देखकर ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. घबराइए नहीं, कल तक वे सीधे रास्ते पर आ जाएंगे. लेकिन यह बताइए कि उनके चिल्लाने पर आप इतना घबरा क्यों गईं. अब तक तो आप बड़ी बहादुरी से हमारे सवालों का जवाब दे रही थीं लेकिन अब क्या हो गया है?

अमिता: आप जानना क्या चाहते हैं? मैं तो समझ नहीं सकती.

यही हाल उन लोगों का भी है जो जुलाई के आखिर में बैडमिंटन के नामी खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या के बाद से इस रहस्य को जानने में दिलचस्पी ले रहे थे. मोदी की पत्नी

संजय सिंह की बेटियों के साथ सैयद मोदी और अमिता: कोई दरार नहीं

अदालत से बाहर निकलते संजय सिंह (बीच में): आक्रामक मुद्रा

अमिता और उनके दोस्त संजय सिंह से की गई पूछताछ का ऊपर दिया गया अंश बताता है कि इस हत्या का रहस्य जानने में लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों है.

बंबइया फिल्मों के किसी पटकथा लेखक का दिमाग भी इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाता. यह हत्या, सेक्स, खेल और राजनीति जैसे सनसनीखेज मसालों का जबरदस्त घालमेल है. बेहद प्रतिभाशाली और बड़े लोगों से जुड़े सैयद मोदी की जब हत्या हुई तो किसी को कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ आ रहा था. फिर यह संदेह जाहिर किया गया कि उनकी पत्नी के, जो खुद नामी खिलाड़ी हैं, सैयद मोदी के गहरे दोस्त और नेता संजय सिंह से अवैध संबंध हैं. इनके चलते संजय ने ही मोदी को मरवाकर प्रेम की राह में इस रोड़े को साफ करवा दिया.

लेकिन पिछले पखवाड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संजय को गिरफ्तार करने के साथ ही मामला अपने असली रंग में आ गया. राजनीति के मैदान में भी यह सनसनीखेज मामला उसी तरह छा गया जैसे खेल के मैदान में सैयद मोदी छा गए थे. बहुत संभावना है कि संजय सिंह के जुड़े होने से यह साल का सबसे चर्चित राजनैतिक मुद्दा बने.

पिछले साल इंका छोड़कर वी.पी. सिंह के जनमोर्चे में आए संजय सिंह के राजनैतिक जीवन के लिए यह मुद्दा आर-पार वाला है. उनको और उनके काम करने के ढंग को

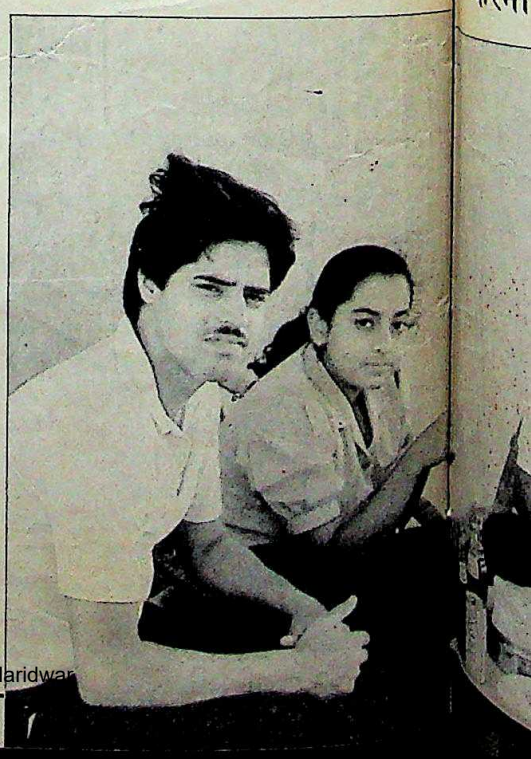

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जानने वालों का कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने को प्रमुखता से स्थापित करने के लिए संजय सिंह को यह एक अच्छा मौका मिला है.

वैसे भी संजय सिंह किसी की पैरवी या सरक्षण से राजनीति में नहीं बढ़े हैं. संजय गांधी के जमाने में एकदम सड़क की राजनैतिक लड़ाई से शुरू करके उन्होंने अपने आपको अमेठी में 'राजीव का आदमी' के रूप में स्थापित किया. उत्तर प्रदेश में मंत्री रहते उन्होंने अपनी राजनैतिक ताकत बढ़ाई. फिर उन्होंने वी.पी. सिंह के इलाहाबाद उपचुनाव में सफल अभियान संचालित किया. वे गंदी राजनीति का हर दांवपेच जानने वाले नेता हैं और यह खेल खेलने में माहिर भी.

उनके खिलाफ सबूत चाहे जो हों लेकिन सरकार और सीबीआई ने जिस अनाड़ीपन से शुरू से अब तक मामला निबटाया है, उस पर राजनैतिक षड्यंत्र रचने का आरोप आसानी से लग गया है. मामला अगर इसी तरीके से चला तो निश्चय ही संजय सिंह इसका लाभ भी उठाएंगे ही.

अब पूरा मामला असली मंशा पर आ टिका है. संजय सिंह ने अपने बेहतरीन दोस्त की हत्या क्यों की? सवाल इतना ही नहीं बल्कि यह भी है कि सरकार द्वारा उन्हें हत्यारा बताने के पीछे मंशा क्या है. इस स्थिति में वैसे सरकार की मंशा का सवाल अधिक महत्वपूर्ण है. मौका न चूकने वाला, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा यह नेता देखने-सुनने में खूबसूरत है, जिससे महिलाएं इसकी खास प्रशंसक बन जाती हैं. अब वे प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र अमेठी में एक बड़ी हस्ती बनकर उभरे हैं. यही बात इस पूरे प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है कि प्रधानमंत्री के लिए खतरा बन जाने की आशंका में ही कहीं सीबीआई उन्हें परेशान तो नहीं कर रही है? या फिर सचमुच सैयद मोदी की पत्नी से अपने संबंध बनाए रखने के लिए ही उन्होंने अपने करीबी दोस्त की हत्या तो नहीं करवा दी?

सरकारी एजेंसियों ने जिस तरह से इस मामले को अभी तक निबटाया है उससे निश्चय ही विपक्ष के इस आरोप को बल मिलता है कि यह एक राजनैतिक षड्यंत्र है.

मामले की दो गुत्थियां हैं— संजय सिंह ने अपने करीबी दोस्त मोदी की हत्या क्यों की, और सरकार उन्हें हत्यारा क्यों साबित करना चाहती है

सैयद मोदी के साथ संजय सिंहः दोस्ताना ताल्लुकात

दूरदर्शन ने इस मामले में न सिर्फ अमिता की कथित डायरी और मोदी की हत्या के लिए संजय सिंह द्वारा बुलवाए गए कथित हत्यारों के इकबालिया बयान वगैरह के समाचार दिए बल्कि संजय सिंह के लखनऊ वाले बंगले पर पड़े सीबीआई के छापे की चित्रमय रिपोर्ट भी दी. इससे लगता है कि उसे छापा डालने की सूचना पहले से थी और इसे कवर करने के निर्देश भी थे.

इसी प्रकार सीबीआई के लोग लखनऊ में संवाददाताओं को जांच की प्रगति का दैनिक ब्यौरा देते आ रहे हैं. वे हरदम यही कहते आए हैं कि संजय सिंह के खिलाफ मामला एकदम सही है और हत्या का उद्देश्य उनके और अमिता के बीच अवैध संबंध बनाए रखना है. सामान्य परिस्थितियों में सीबीआई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इलाहाबाद उप-चुनाव में वी.पी. सिंह की जीत के बाद फीके-से पड़ गए जनमोर्चा में इस हत्याकांड से उठे विवादों ने मानो जान डाल दी है

कभी अपनी जांच के दौरान प्रेस के लोगों को कुछ नहीं बताती और इस प्रकार के सनसनी-खेज मामलों में तो कतई नहीं.

दरअसल, संजय सिंह को अपनी गिरफ्तारी की उम्मीद थी भी. लखनऊ में सीबीआई की शुरुआती पूछताछ के बाद वे अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी लौट आए और वहां उन्होंने कई बड़ी सभाओं को संबोधित किया. गौरीगंज में 2 सितंबर को हुई ऐसी दूसरी सभा के बाद उन्होंने 'इंडिया टुडे' को बताया, "अब वे जानेंगे कि इन सभाओं का क्या असर हुआ है तो कल ही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे." और उनकी बात ठीक निकली.

आर.के. गुप्ता

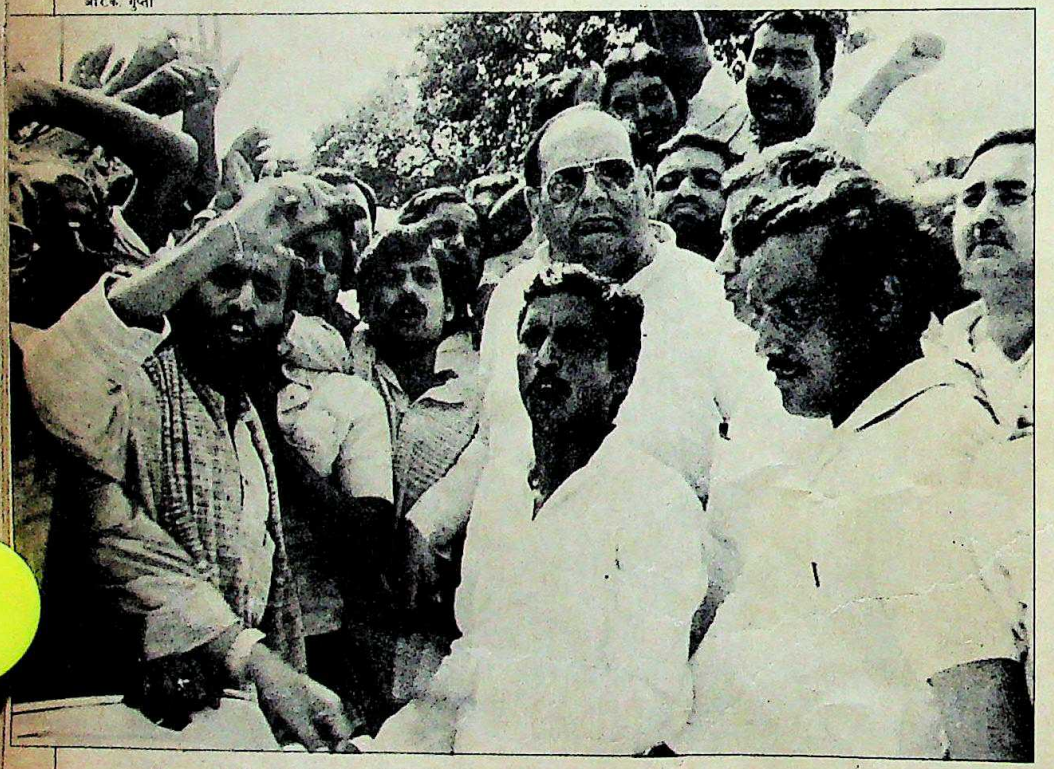

अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते अरुण नेहरू (बीच में)

पर जिस भरोसे से सीबीआई के लोग अखबारवालों को यह बताते रहे कि संजय सिंह ही अपराधी हैं, वैसा कोई बड़ा सबूत उन्होंने 3 सितंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश नहीं किया. मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के अलावा उन्होंने सिर्फ यही नई बात जोड़ी कि हत्या की योजना वी.पी. सिंह की इलाहाबाद जीत के बाद आयोजित एक पार्टी में बनाई गई थी.

अखबारवालों को सीबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह पार्टी जून के तीसरे हफ्ते में इलाहाबाद के यात्रिक होटल में हुई. सीबीआई के पास इस बात के 'दस्तावेजी और दूसरे सबूत' हैं कि इस पार्टी में संजय सिंह और हत्या के आरोप में पहले पकड़ा गया अखिलेश सिंह भी मौजूद था और दोनों ने षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार की.

संजय सिंह को पुलिस रिमांड देने की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने ऐसे सबूत होने का दावा किया कि अखिलेश सिंह ने 29, 30 और 31 जुलाई को (मोदी की हत्या 28 जुलाई को हुई थी) दिल्ली में संजय सिंह से संपर्क करने की पुरजोर कोशिश की थी. लेकिन सीबीआई ने यह नहीं बताया कि उसके पास संजय सिंह और अखिलेश सिंह द्वारा हत्या की साजिश रचने का कौन-सा सबूत है. पार्टी में वे दोनों मौजूद थे, इतने भर से यह बात साबित नहीं हो जाती.

अभी तक सीबीआई ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. उसने अमिता, उनके मां-बाप, संजय सिंह के यहां काम करने वालों और मोदी के साथ बैडमिंटन खेलने वालों समेत लखनऊ और दिल्ली के अनेक लोगों से पूछताछ की है.

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में पत्रकारों को बताया, "जब हम चार्जशीट दाखिल करेंगे तो आप उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ़ पाएंगे." लेकिन अभी तक इस मामले में जितने पोल दिख रहे हैं उससे तो यह दावा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा ही दिखाई देता है.

सीबीआई का मानना है कि मोदी की हत्या भाड़े के चार हत्यारों ने की जिन्हें अखिलेश सिंह ने तैयार किया. इस समय जनमोर्चा के कार्यकर्ता अखिलेश रायबरेली के एक पूर्व नेता के पुत्र हैं जिनके संबंध अपराधियों से बताए जाते थे. सीबीआई का कहना है कि अखिलेश ने संजय सिंह के कहने पर ही यह अपराध करवाया और संजय के अमिता से नाजायज ताल्लुकात थे.

अपनी बात के पक्ष में सीबीआई ने निम्नलिखित सबूत पेश किए हैं.

- ▶ अमिता मोदी की एक डायरी.
- ▶ मोदी दंपती की एक दर्जन चिट्ठियां.
- ▶ सैयद मोदी की डायरी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या के पहले की एक चिट्ठी लिखी है.
- ▶ अखिलेश सिंह और हत्या में प्रयोग की गई मारुति वैन के ड्राइवर जीतेंद्र सिंह उर्फ टिंकू के 'इकबालिया बयान.'
- ▶ अमिता और उनकी मां के बीच हुआ पत्र-व्यवहार.
- ▶ आत्महत्या की धमकी देते हुए लिखी गई संजय की पत्नी गरिमा सिंह की चिट्ठी.
- ▶ अमिता के सास-ससुर के बयान जिससे मियां-बीवी के बीच खटपट की पुष्टि होती है.
- ▶ मोदी के घर के एक पूर्व नौकर का बयान जिससे भी इस झगड़े की पुष्टि होती है.
- ▶ हत्या में उपयोग किए गए हथियार (38 मिमी रिवाल्वर) की वैज्ञानिक जांच से पुष्टि की रिपोर्ट.
- ▶ पहचान परेड के दौरान हत्या के तीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चश्मदीद गवाहों में से एक, प्रेमचंद यादव
द्वारा दो हत्यारों अमर बहादुर सिंह और
भगवती सिंह की पहचान.
▸ झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने दिए
गए अखिलेश और टिंकू के बयान और
▸ जून में संजय सिंह और अखिलेश की
मुलाकात की पुष्टि करने वाले दस्तावेज.

अधिकांश दस्तावेज यही बताने के लिए जुटाए गए हैं जिससे साबित हो कि संजय सिंह और अमिता के बीच नाजायज ताल्लुकात थे तथा मोदी और अमिता के बीच संजय के कारण तनाव रहता था. अदालत में शायरियों और चिट्ठियों को पेश करते हुए सीबीआई ने स्पष्ट कहा कि संजय और अमिता के बीच विवाहेतर संबंध थे जिसका मोदी विरोध कर रहे थे.

पुलिस रिमांड में रहते हुए अमिता ने माना कि संजय सिंह से उनके बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं लेकिन विवाहेतर संबंधों का उन्होंने जोरदार खंडन किया. उन्होंने कहा, "संजय सिंह हमारे करीबी पारिवारिक मित्र और शुभचिंतक थे. इसीलिए मैंने अपनी डायरी में उनका जिक्र किया है. लेकिन यह कहना एकदम गलत है कि ऐसा मैंने उनसे विवाहेतर संबंधों के कारण किया है क्योंकि ऐसे संबंध कभी थे ही नहीं." उन्होंने आगे कहा, "दरअसल मोदी मुझे बहुत चाहते थे और मैं उन्हें चिढ़ाने के लिए भी कुछ उल्टी-सीधी बातें डायरी में लिख देती थी. यह डायरी मोदी के लिए थी, सीबीआई के लिए नहीं. मोदी मेरी डायरी की हर पंक्ति पढ़ते थे और जब भी मुझे उन्हें सताने का मन होता, मैं डायरी में कुछ न कुछ ऐसा लिख देती थी. अगर यह किसी से मेरे रिश्तों का लेखा-जोखा होता तो मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि इसे यों ही पड़ा रहने देती जिससे सीबीआई वाले केस बना लें. हत्या के 17 दिनों के बाद सीबीआई ने मेरे घर पर छापा मारा और अगर मैं चाहती तो इस बीच डायरी कहीं छुपा सकती थी."

वे इस बात का भी खंडन करती हैं कि उन्हें मोदी द्वारा लिखी गई छह पेज की कोई चिट्ठी कभी मिली थी जिसे सीबीआई आत्महत्या से पहले की चिट्ठी होने का दावा करती है. दरअसल पूछताछ के दौरान इस चिट्ठी को पढ़ने और इसकी लिखावट देखने के बाद उन्होंने इसके असली होने पर ही शंका जाहिर की थी. उन्होंने कहा, "मोदी की लिखावट बहुत टेढ़ी-मेढ़ी थी लेकिन यह चिट्ठी बहुत अच्छी लिखावट में है. मोदी के एक करीबी दोस्त को भी जब सीबीआई ने यह चिट्ठी दिखाई तो उसने भी इसे मोदी की लिखाई मानने से इनकार कर दिया था."

चिट्ठी में न तो तारीख का जिक्र है, न जगह का. सीबीआई का मानना है कि यह चिट्ठी हाल ही में लिखी गई थी. वह अमिता पर दबाव डालती रही कि वे चिट्ठी पाने की तारीख बताएं. अमिता कहती हैं, "मैंने वह चिट्ठी कभी देखी ही नहीं. मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मोदी कभी इतनी कड़ी चिट्ठी मुझे लिख सकते थे."

संजय सिंह और अमिता के वकीलों ने अदालत में जिरह के समय सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर भारी संदेह जाहिर किया. वकीलों का कहना था कि इन दस्तावेजों से तो ज्यादा से ज्यादा संजय सिंह, अमिता और सैयद मोदी के बीच घनिष्ठ संबंध ही जाहिर होते हैं.

नौ दिन की हिरासत के बाद अखिलेश सिंह को जब अदालत में पेश किया गया तो उसने भी कोई इकबालिया बयान देने की बात का खंडन किया. उसके वकील ने अदालत को दी एक अर्जी में कहा कि उसके मुवक्किल को हिरासत में मानसिक यातनाएं दी गईं और सादे कागजों पर जबरन दस्तखत कराए गए.

गरिमा सिंह की जिस चिट्ठी में आत्महत्या की कथित धमकी का जिक्र है, वह भी अमेठी में संजय के खिलाड़ी दोस्तों द्वारा उनका जन्मदिन मनाने के बारे में है (संजय खुद भी बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं और अक्सर मोदी दंपती के साथ खेला करते थे). इस बारे में संजय सिंह कहते हैं, "हम लोगों के घर में पर्दा प्रथा है इसलिए इस आयोजन में भाग न ले पाने के कारण मेरी पत्नी बहुत नाराज थी. अपने राजनैतिक कामकाज के कारण मैं उन

इस मामले को दूसरे दलों ने भी उठाया है. उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमेठी में बंद का आयोजन किया गया और गिरफ्तारियां भी दी गईं

प्रशांत पंजियार

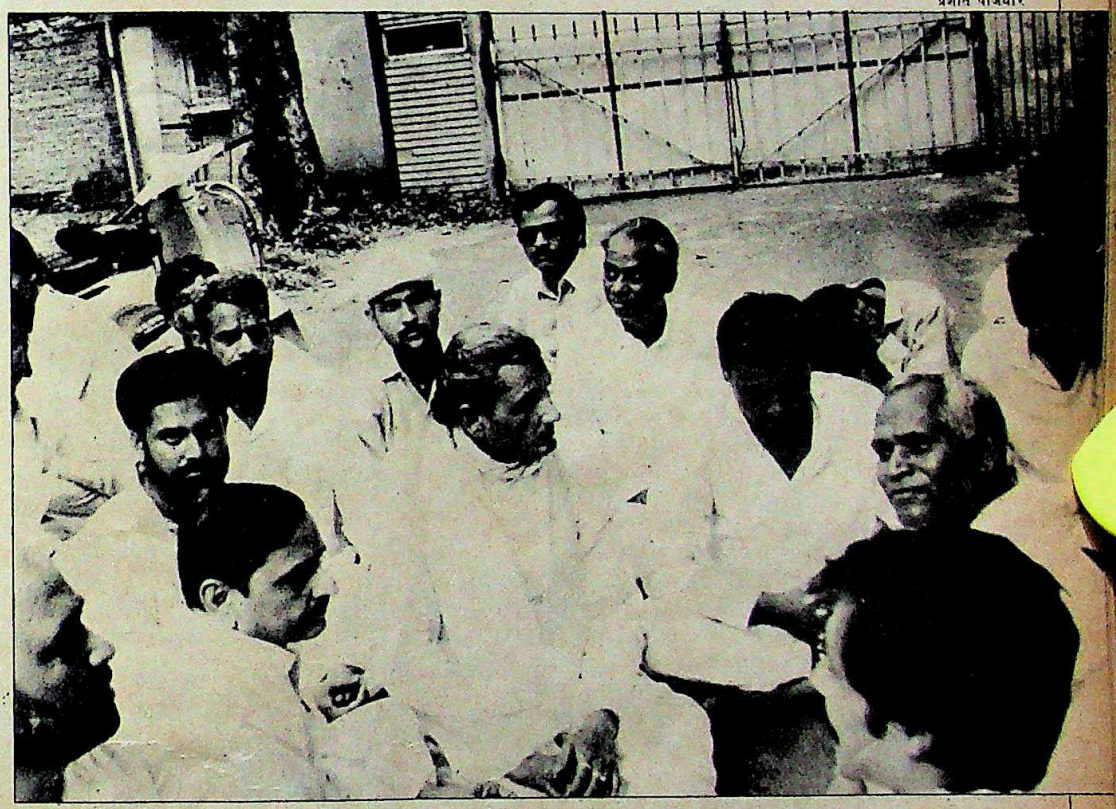

विपक्षी दलों के विधायकों, नेताओं का संजय सिंह के निवास के बाहर धरना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिनों घर में समय नहीं दे पाया और जन्मदिन पर भी उन लोगों का साथ नहीं दे पाने से वह बहुत परेशान हो गई. हर राजनैतिक व्यक्ति की पत्नी के जीवन में ऐसी कुंठा कभी न कभी आती ही है.'' उन्होंने सफाई भी दी कि उनकी पत्नी की चिट्ठी में अमिता मोदी का कोई जिक्र नहीं था.

अपनी इस कहानी को सही साबित करने के लिए कि अमिता-संजय संबंधों के चलते मोदी दंपती में खटपट होती रहती थी, सीबीआई ने उनके घर में नौकर रह चुके गोरखपुर के एक 14 वर्षीय लड़के की गवाही ली. अमिता के अनुसार यह लड़का उनके घर में दो हफ्ते ही रहा और इतने समय में ही वह पति-पत्नी के रिश्तों को भी जान ले, इसका सवाल ही नहीं उठता. अमिता कहती हैं, ''कभी-कभार हमारी कहा-सुनी हो जाती थी पर मामला कभी गंभीर नहीं बना. मेरे मां-बाप जब भी यहां आते थे तो हमारे बेडरूम के बगल वाले कमरे में ही सोते थे लेकिन उन्होंने भी कभी कोई चिक-चिक नहीं सुनी. अभ्यास के समय वह बहुत सुस्त रहते थे सो मैं सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट में ही उनसे तेज-आवाज में बात करती थी.''

पहली सितंबर को लखनऊ जेल में अपराधी की शिनाख्त के लिए जो परेड हुई उससे भी सीबीआई को मनमाफिक परिणाम नहीं मिल पाया. इसी में दो कथित हत्यारों अमर बहादुर सिंह और भगवती सिंह की शिनाख्त हुई. सीबीआई की कहानी के मुताबिक अमर बहादुर ने गोली चलाई जबकि भगवती हिफाजत कर रहा था. हत्या के तीन चश्मदीद गवाह हैं पर हत्यारों की शिनाख्त प्रेमचंद यादव ही कर पाया जिसकी स्टेडियम के गेट के सामने छोटी सी दुकान है.

गेट के पास पान बेचने वाली औरत कैसर और रिक्शाचालक किशन बहादुर ने (जिसे स्थानीय पुलिस ने पहले सीताराम बताया था) तीन बार शिनाख्त परेड में हिस्सा लिया पर वे हत्यारों को नहीं पहचान पाए.

हजरतगंज थाने में के.डी. सिंह बाबू स्पोर्ट्स स्टेडियम के एक अधिकारी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गोली चलने की आवाज सुनकर दुकानदार यादव उलटी तरफ यानी स्टेडियम के अंदर भागा था. बाकी दो गवाह स्टेडियम गेट के बाहर होने के कारण हत्या स्थल के ज्यादा करीब थे. और फिर, पुलिस को मारुति वैन का नंबर बताने वाला रिक्शाचालक किशन बहादुर निश्चित रूप से इस स्थिति में होगा कि उसे हत्यारे भी अच्छी तरह दिखाई दिए होंगे.

सीबीआई के केस में इन बड़ी पोलों के अलावा संजय और अमिता द्वारा षड्यंत्र रचने की बात में भी दो बड़े सवाल अनुत्तरित रह गए हैं. एक, अपराध के लिए तुरंत कारण क्या बना? दूसरा, मोदी की हत्या से अमिता और संजय सिंह को क्या फायदा हो सकता है?

सीबीआई की जांच बताती है कि संजय और अमिता बहुत घनिष्ट थे या एक दूसरे से प्रेम करते थे या 1985 से ही उनके विवाहेतर संबंध थे, हालांकि उनकी मित्रता 1984 से ही चली आ रही थी. अगर मधुर संबंध इतने समय से चले आ रहे थे तो अब अचानक मोदी की हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक बड़े पुलिस अधिकारी कहते हैं, ''अगर अमिता-संजय के बीच कोई मामला था तो कायदे से मोदी को ही संजय की हत्या करनी चाहिए थी.''

अगर ऐसे संबंध थे तो इसे आराम से चलने रहते देने के लिए मोदी का जिंदा रहना ही ज्यादा 'सुविधाजनक' होता. दावे के मुताबिक अगर ये रिश्ते चार साल से चले आ रहे थे तो मोदी को इसका पता न हो, यह असंभव है. अगर उन्होंने इतने समय तक चुप्पी साधे रखी होती तो यह स्थिति उन दोनों के लिए अच्छी ही होती. दोनों ही शहर भर में जाने-माने हैं. ऐसे में मोदी के न रहने से उनको अपने रिश्ते बनाए रखना अधिक मुश्किल हो जाता. इतना ही नहीं, संजय सिंह के अनेक राजनैतिक दुश्मन हैं और उन्हें खुद भी इसका भलीभांति एहसास है.

मोदी दंपती के जिन करीबी दोस्तों से सीबीआई ने पूछताछ की, उन सबने उन दोनों की बीच कोई तनाव होने का खंडन किया है. मियां-बीवी बहुत नामी थे पर वे संजय सिंह सरीखे एक-दो करीबी

एस प्रेमी

अमिता मोदी

'सचाई मेरे हक में है'

*चौबीस वर्षीया अमिता मोदी का जीवन एकाएक दुःस्वप्नों से घिर गया. रातोरात वे सीबीआई का निशाना बन गईं. खुफिया एजेंसी का इलजाम है कि उन्होंने पति की हत्या की खातिर अपने कथित प्रेमी के साथ साजिश रची. पुलिस हिरासत में रहने की भयावह यंत्रणा भोगने के बाद लखनऊ के अपने फ्लैट में अपनी छह महीने की बिटिया के पास लौटने पर अब वे पहले के मुकाबले मजबूत और संयत नजर आने लगी हैं. **'इंडिया टुडे'** के साथ हुई उनकी बातचीत के अंश:*

- ***पति की मृत्यु पर***

पति की मौत से मुझे गहरा आघात लगा है. मैं उनका मातम भी नहीं मना पाई थी कि सीबीआई ने उनकी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर मुझे उससे भी गहरा आघात पहुंचाया.

- ***अपनी गिरफ्तारी पर***

मुझे 14 विचाराधीन बंदी महिलाओं के साथ जेल बैरक में रखा गया. मैं पूरी रात सो नहीं पाई. इसका कारण ईंटों का फर्श या बंदी महिलाओं का संग नहीं बल्कि वहां पहुचने की यंत्रणा थी. तब मुझे मोदी की बेतरह याद आई. वे होते तो वह दिन न देखना पड़ता.

- ***भविष्य की योजनाओं पर***

जब वर्तमान ही अनिश्चित हो तो भविष्य के बारे में कैसे कुछ सोचा जा सकता है. पता नहीं सीबीआई कब क्या कर बैठे. जैसे ही वे इजाजत देंगे, मैं बंबई चली जाऊंगी. अपनी बेटी आकांक्षा को मैं बंबई में ही पालूंगी और पढ़ाऊंगी. लेकिन इस मुकदमे के सिलसिले में मुझे लखनऊ आते रहना पड़ेगा. लखनऊ से बस अब मैं इतना ही संबंध रखना चाहती हूं.

- ***जिस यंत्रणा से वे गुजरीं***

यातना का यह दौर मुझे तबाह कर सकता था लेकिन मैं सचाई जानती हूं और यह मेरे हक में ही है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोस्तों के सिवा दूसरों से ज्यादा मेल-मिलाप नहीं रखते थे. दरअसल दोनों ही परंपरागत परिवारों से हैं और इस तरह के प्रेम त्रिकोण या खुले सेक्स संबंधों के लिए अनुकूल नहीं दिखते. सीबीआई अमिता को जिस तरह से सेक्सी बताने की कोशिश कर रही है, वैसी वे हैं नहीं. वे खिलाड़ी भले ही हैं पर एकदम साधारण दिखने वाली और घरेलू महिला हैं. बैडमिंटन की राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकने के बावजूद वे नकचढ़ी कभी नहीं रहीं.

सीबीआई के लोग इन दिक्कतों से वाकिफ हैं. अपनी कहानी को रंग चढ़ाने के लिए वे दिन-रात काम किए रहे. उनका मानना है कि छह महीने पहले अपनी बेटी आकांक्षा के जन्म के बाद मोदी जिंदगी में कुछ नई खटपट हुई. 5 सितंबर को सीबीआई ने पत्रकारों को बताया कि मोदी को आकांक्षा के वैध संतान होने पर शक था. इसी कारण अमिता ने महीने भर की आकांक्षा को बंबई में उसके नाना-नानी के पास छोड़ दिया. अपराध का तात्कालिक कारण भी यही बना. अमिता इस बात का जोरदार खंडन करती हैं, "हम लोग कड़े प्रशिक्षण-अभ्यास के लिए बंबई चले जाना चाहते थे. इसी बात को ध्यान में रखकर आकांक्षा को नाना-नानी के पास छोड़ा गया."

अखिलेश और अमिता के वकीलों के अनुसार सीबीआई इन दोनों पर दबाव डाल रही है कि वे इकबालिया गवाह बन जाएं और संजय को इस हत्या के लिए दोषी बताएं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा.

गिरफ्तारी के दूसरे दिन 4 सितंबर को जब संजय सिंह को भी अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत से कुछ खास बयान देने की इजाजत मांगी. अनुमति मिलने पर उन्होंने उस सीबीआई अधिकारी का नाम लिया जिसने उन्हें 3 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद देर रात को सबसे पहले यही पूछा कि क्या वे लोकसभा या विधानसभा के लिए अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं. इस अधिकारी ने, जो इस मामले की जांच भी कर रहा है, पूछा कि "क्या आपको पता है कि राजीव गांधी के मुकाबले चुनाव लड़ने का क्या अंजाम होता है." संजय ने अदालत से कहा, "सर, मैं सैयद मोदी की हत्या और राजीव गांधी से अपने रिश्तों के बीच किसी भी सूत्र को समझ पाने में असमर्थ हूं."

संजय सिंह ने जिस अधिकारी का नाम लिया वह अदालत में हाजिर था. उसने ऐसा सवाल पूछे जाने का खंडन किया. लेकिन यह इस बात का संकेत भी था कि मामला बड़ी तेजी से राजनैतिक रंग पकड़ता जा रहा है.

इस विवाद ने जनमोर्चा को भी एक बार खबरों में ला दिया जो इलाहाबाद उपचुनाव के बाद दब-सा गया था. इस मामले को दूसरे राजनैतिक दलों ने भी उठाया और अमेठी के अधिकांश मतदाता इसे संजय के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र मानते हैं. उनके मन का पता बेहद गर्मी के बावजूद जनमोर्चा की सभाओं में भारी उपस्थिति से भी चलता है.

इसके विपरीत अमेठी में इंका नेताओं की पूछ बहुत कम हो गई है. पिछले महीने जब केंद्रीय संचारमंत्री बीरबहादुर सिंह और अमेठी के मामले देख रहे राजीव गांधी के खास दोस्त सतीश शर्मा यहां आए थे तो यह बात स्पष्ट देखने में आई. लोगों में उत्साह न देखकर उन्होंने जनसभाएं करने की योजना छोड़ दी. इसकी जगह उन्होंने अमेठी क्षेत्र के भेतुआ प्रखंड के ग्राम प्रधानों की बैठक बुलाई. 49 ग्राम प्रधानों में से 12 ही इस बैठक में आए.

इस बीच, संजय सिंह के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में इस वीआईपी चुनाव क्षेत्र में लगातार बंद का आयोजन किया है और स्वैच्छिक गिरफ्तारियां दी हैं. इससे इंका के खेमे में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है. 13 और 14 अगस्त को यहां सोनिया गांधी, 25 और 26 अगस्त को बीरबहादुर सिंह और सतीश शर्मा तथा 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के दौरों से बेचैनी साफ दिखती है.

सीबीआई के जांच शुरू करने के बाद ही इन महत्वपूर्ण लोगों के अचानक दौरों से लोगों के मन में एक बात घर कर गई है. वह यह कि अगर सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश नहीं करती तो संजय सिंह भी वी.पी. सिंह की तरह विपक्षी अभियान के 'शहीद' बन जाएंगे.

—विलीप अवस्थी, लखनऊ और अमेठी में

आर.के. गुप्ता

गरिमा सिंह

'मेरे पति बेकसूर हैं'

संजय सिंह की 32 वर्षीया पत्नी गरिमा सिंह सैयद मोदी हत्याकांड की एक और प्रमुख पात्र हैं. वे पति पर लगे आरोपों की यंत्रणा झेलने को विवश हैं. सीबीआई ने उनसे भी डेढ़ घंटे तक कड़ी पूछताछ की. राजघराने से संबंध रखने वाली गरिमा (वे वी.पी. सिंह के सौतेले भाई की बेटी हैं) अपने विशाल लेकिन जर्जर हो चले महलनुमा घर में गुमनाम-सी रह रही थीं. उनके पति के राजनीति में आने के बाद यही जर्जर महल अमेठी के राजा का घर बन गया था. संजय सिंह के साथ उनकी शादी दिसंबर 1973 में हुई. तब वे कुल 18 साल की और संजय 21 साल के थे. दो बेटियां और एक बेटे की मां गरिमा ने पिछले पखवाड़े ***'इंडिया टुडे'*** *को इंटरव्यू दिया.*

● ***अपनी यंत्रणा के बारे में***

हम अपने ससुर का क्रियाकर्म भी ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि सीबीआई हमारे पीछे पड़ी थी. यहां पहुंची तो पूरे घर को अस्त-व्यस्त पाया. घर के बरतन-भांडे यहां तक कि रद्दी की टोकरी की तलाशी भी उन्होंने ले डाली थी. लेकिन उन्हें सबूत का एक कतरा तक न मिला.

● ***सीबीआई ने उनसे क्या पूछा***

मैं हैरान हूं कि सीबीआई मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी है. मैं समझ नहीं पा रही कि इस मामले के दूसरे पहलुओं को वे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं.

● ***मोदी परिवार के साथ उनकी दोस्ती पर***

मोदी परिवार के साथ हमारी दोस्ती थी और अब भी है. मेरे पति के अमिता के साथ किसी तरह के संबंध होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. अखबारवालों से मेरी गुजारिश है कि तथ्यों को छापने से पहले छानबीन करें क्योंकि जो सूचनाएं उन्हें दी जा रही हैं वे गलत हैं.

● ***पति पर लगे आरोपों पर***

मैं जानती हूं कि मेरे पति बेकसूर हैं. और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वे इस षड्यंत्र से बेदाग निकल आएं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कांग्रेस (इ)

जान फूंकने की जद्दोजहद

आत्म-विश्लेषण और चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन के पुनर्गठन का दौर

माहौल लगभग वही जाना-पहचाना था जो आम तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की बैठकों का होता है. नई दिल्ली के तालकटोरा उद्यान में बने मंच की पृष्ठभूमि उन्हीं जाने-पहचाने नेताओं के चित्रों से सुशोभित थी और मंच की शोभा उसी पुराने अंदाज में बढ़ा रहे थे राजीव गांधी और उनके अगल-बगल बैठे वरिष्ठ पार्टी नेता. 5 से 8 सितंबर तक चली इस बैठक में इंकाई मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, जिला अधिकारियों और दूसरे प्रमुख नेताओं सहित करीब 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. खूब भाषण हुए लेकिन पिछली बैठकों की तुलना में इस बार एक भारी अंतर था जिससे इस बैठक के स्वरूप का पता चलता है. इसे 'पार्टी निर्माण पर राष्ट्रीय गोष्ठी' की संज्ञा दी गई थी. लेकिन पार्टी के लोगों का जोश-खरोश मंदा दिख रहा था.

पिछली बैठकों की तरह इस बैठक में चारण वृत्ति का अभाव दिखा. ऐसा नहीं था कि राजीव की रास कमजोर हो गई हो. वे वहां बिलकुल मौजूद थे. लेकिन उन्हें करीब 100 वक्ताओं की बातें सुननी ही पड़ीं. इन वक्ताओं ने गंभीर चेतावनियां दीं कि अगर पार्टी आलाकमान और इंका शासित राज्यों की सरकारों ने अपने कामकाज के रवैये में भारी तब्दीली नहीं की तो अगले चुनाव में पार्टी को बुरी तरह मुंह की खानी होगी.

इन्हीं आशंकाओं से त्रस्त दिखे पार्टी के वे 120 सदस्य भी जिन्होंने इंका कार्यसमिति की दो दिन की बैठक में भाग लिया. यह गंभीर बैठक तालकटोरा में हुई गोष्ठी के बाद ही संसद के चार समिति कक्षों में हुई. इसमें राजीव ने भी भाग लिया. इसमें चुनाव के पहले पार्टी को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कई सुझाव रखे गए. इन बैठकों में प्रेसवालों को आने की बिलकुल इजाजत नहीं दी गई. बैठक में भाग लेने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई थी कि वे बाहर पत्रकारों से बैठक के बारे में एक लफ्ज भी न कहें. इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद ने बताया, "बैठक में लोगों की भागीदारी और चर्चाओं से तो यही संकेत मिलता है कि पार्टी किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार है. कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. यह सब आत्म-निरीक्षण और सही कार्रवाई से संभव हो पाया है."

'सही कार्रवाई' में कई तरह की गतिविधियां निहित थीं. दोनों बैठकों की समाप्ति के चंद दिनों के भीतर ही राजीव ने और विचार-विमर्श के लिए पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया, पूर्व सूचना और प्रसारणमंत्री विट्ठल गाडगिल को पार्टी महासचिव नियुक्त किया और तीन प्रदेश इंका समितियों का पुनर्गठन किया. इससे पहले उन्होंने पूर्व दिग्गज नेताओं श्यामाचरण शुक्ल और नंदिनी सत्पथी को पार्टी में शामिल किया था और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के लिए समन्वय समितियां नियुक्त की थीं.

जाहिर है इंका राजीव के नेतृत्व में बड़ी लड़ाई लड़ने की व्यापक तैयारी कर रही है. राजीव की रणनीति यही दिखती है कि पुराने नेताओं को आकर्षक पदों पर बैठाकर संतुष्ट रखा जाए और युवा नेताओं को अतिरिक्त बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं. और यह दिखाने के लिए कि राजीव पार्टी के कामकाज के प्रति बहुत गंभीर हैं, उन्होंने पिछले पखवाड़े हुई पार्टी की विभिन्न बैठकों में किए गए फैसलों को लागू करने के लिए समय सीमा तय कर दी. गाडगिल ने कहा, "मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हरेक कांग्रेसी को अगले संसदीय चुनावों तक अपने-अपने लक्ष्य समय पर हासिल कर लेने होंगे. सभी लोगों को स्पष्ट कार्य योजना दी गई है जो उन्हीं के सहयोग से बनाई गई है."

इंका कार्यसमिति द्वारा तैयार समयबद्ध योजना के अनुसार, राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशों पर सुझाव हासिल करने के लिए उन्हें प्रदेश इंका समितियों के पास भेजा

CC-0. Prof. Satish Kumar. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाएगा. वहां से सुझाव आ जाने के बाद इस महीने के आखिरी हफ्ते में इंका कार्यसमिति की फिर दो दिन की बैठक होगी जिसमें पंचायती राज तथा पार्टी संगठन के पुनर्गठन के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा. और इन सबकी पुष्टि के लिए अखिल भारतीय इंका अधिवेशन नवंबर में बिहार में होगा. इस अधिवेशन में पार्टी अपने आर्थिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप भी देगी जिसके आधार पर 1989-90 का केंद्रीय बजट बनाया जाएगा. और अंत में नवंबर 1989 में इलाहाबाद में इंका की विशाल बैठक होगी जिसमें 10,000 पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे. इसमें पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा. गाडगिल कहते हैं, "प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे चाहते हैं पार्टी उन्हें बताए कि सरकार को क्या करना चाहिए. वे हर मसले पर पार्टी का आदेश चाहते हैं."

प्रधानमंत्री अब अपनी पार्टी को कई मोर्चों पर सक्रिय करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कभी-कभी इनमें विरोधाभास और टकराव दिखने लगता है. पार्टी उम्मीद के अनुरूप काम नहीं कर रही है

आज इंका के भीतर जो कुछ हो रहा है, उसके सूत्र दरअसल एक साल पहले प्रधानमंत्री के आदेश पर शुरू हुई गतिविधियों में हैं. उस समय उन्होंने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि ऊपर से प्रेरणा मिलने के बावजूद पार्टी विपक्ष के इन आरोपों का मुकाबला करने और जवाब देने में नाकाम रही है कि राजीव रक्षा सौदों की दलाली में शामिल थे. लिहाजा उन्होंने केंद्र और राज्यों में भरोसेमंद लोगों को पार्टी पदाधिकारी बनाया और उन्हें जिला स्तर पर इंका कार्यकर्ताओं की बैठकें करने और पार्टी के कामकाज पर उनके विचार जानने का आदेश दिया. कोई नौ महीने तक सभी राज्यों में गोष्ठियां हुईं और अंततः राष्ट्रीय गोष्ठी और इंका कार्यसमिति की बैठक में विचार-विमर्श के लिए एक 22-पेजी दस्तावेज तैयार किया गया. इसमें पंचायती राज प्रणाली से लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन तक पर सुझाव हैं. 'इंडिया टुडे' ने यह अहम दस्तावेज खास तौर पर हासिल किया है. इसकी कुछ सिफारिशें इस तरह हैं. :

- ▸ प्रखंड और जिला स्तर पर पार्टी चुनाव जल्द से जल्द हों;
- ▸ जिला स्तर पर वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए जाएं ताकि पार्टी कार्यालयों को दिन में देर तक खुला रखा जा सके;
- ▸ केंद्र और राज्यों में सरकार के कार्यक्रमों में पार्टी का सक्रिय सहयोग हो;
- ▸ खादी का इस्तेमाल आवश्यक बना देना चाहिए और शराबियों को किसी भी कार्यालय में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए;
- ▸ अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए असरदार रणनीति बनाई जानी चाहिए;
- ▸ विपक्षशासित सभी राज्यों में ऐसा जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री राज्य में ही उलझे रहें और वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एका के प्रयासों के लिए अपने राज्य से बाहर न जा सकें;

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस दस्तावेज में पार्टी के कामकाज की आलोचना भी की गई है. अल्पसंख्यकों पर पार्टी की कमजोर होती पकड़ का जिक्र करते हुए इस दस्तावेज में कहा गया है, "देश के कुछ हिस्सों में अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों में पार्टी का पारंपरिक आधार खत्म होता जा रहा है. इसकी वजह इन वर्गों में पार्टी के मजबूत संगठन का न होना है." सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, जिनके विचारों

कार्टून अजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के आधार पर यह दस्तावेज तैयार किया गया है, पार्टी की छवि को लेकर आलाकमान से कहीं ज्यादा चिंतित दिखते हैं. दस्तावेज में मांग की गई है, "नौकरशाहों के भ्रष्टाचार और गंदे कामों में सहभागी इंका कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए."

लेकिन एक ओर जहां राजीव और उनके वरिष्ठ राजनैतिक सहयोगी विचार-विमर्श और पुनर्गठन के जरिये पार्टी में जान फूंकने की कोशिशों में जुटे हैं, वहीं दूसरे कई पार्टी नेताओं को यह सब फिजूल लगता है. उनके अनुसार इसके हानिकारक नतीजे भी हो सकते हैं. पार्टी के कई वरिष्ठ नेता गाडगिल के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति के गठन पर असंतुष्ट हैं. इस समिति में पूर्व युवा इंका अध्यक्ष अंबिका सोनी, तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य जयंती नटराजन, दून स्कूल में पढ़े महाराष्ट्र के भारी-भरकम राज्यसभा सदस्य विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह अहलूवालिया और पंजाब युवा इंका के पूर्व अध्यक्ष पवन बंसल शामिल किए गए हैं. गाडगिल को छोड़ इनमें में कोई भी नेता पार्टी के किसी बड़े पद पर नहीं रहा.

एक वरिष्ठ इंकाई मुख्यमंत्री ने व्यंग्य कसा, "हमने कभी यह कल्पना भी नही की थी कि एक दिन हमारी पार्टी में ऐसा भी दिन आएगा जब ऐसे अनुभवहीन लोग संगठन की किस्मत तय करेंगे और हमें चुनाव जीतने की तरकीब सिखाएंगे."

दूसरे राजनैतिक फैसले भी अड़ंगे जैसे साबित हुए. गलत समय पर उठाए गए कई कदमों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और ओडीसा जैसे राज्यों में पार्टी के लोग चिंतित हो गए हैं. मिसाल के तौर पर राजीव ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मामलों को निबटाने के लिए केंद्रीकृत समन्वय समितियां बनाकर वहां के मुख्यमंत्रियों के अहं को चोट पहुंचाई है. इन समितियों में सभी इंकाई मुख्यमंत्री और प्रदेश इंका अध्यक्ष शामिल हैं. इनके अध्यक्ष गुलामनबी आजाद होंगे.

और इन नए जख्मों पर नमक यह कि दोनों समितियों के कुछ सदस्य इन मुख्यमंत्रियों के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं. मिसाल के तौर पर, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य और केंद्रीय संचारमंत्री बीरबहादुर सिंह के पिट्ठू बलराम सिंह यादव को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और उस समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है जो मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी को निर्देश देगी. पार्टी के प्रमुख लोगों का मानना है कि राजीव के इस कदम से तो तिवारी लगभग अलग-थलग पड़ जाएंगे.

प्रधानमंत्री ने ओडीसा समिति में भी असंतुष्टों को भरकर मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक को चिंतित कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी को पार्टी में शामिल कर लिए जाने से भी पटनायक की स्थिति कमजोर हुई है. उन्होंने सत्पथी की वापसी का जोरदार विरोध किया था.

भवान सिंह

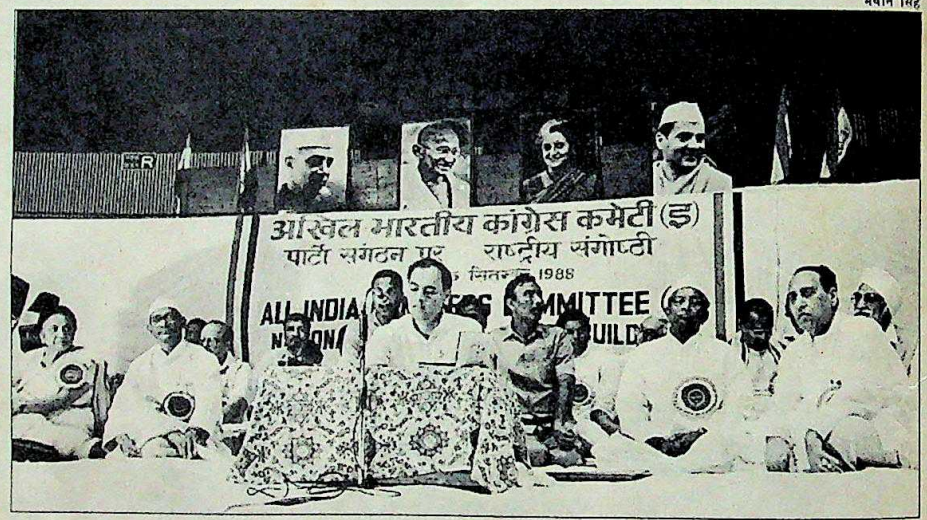

इस बार चारण वृत्ति का अभाव दिखा. बैठक में गंभीर चेतावनी दी गई कि अगर आलाकमान ने अपने कामकाज का रवैया नहीं बदला तो पार्टी चुनाव में बुरी तरह मुंह की खाएगी

सत्पथी के उत्साहित समर्थकों ने अभी से यह बात फैलानी शुरू कर दी है कि आगामी चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बनाए जाने की प्रक्रिया का यह पहला कदम है.

मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है. पार्टी में श्यामाचरण शुक्ल की वापसी से मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के खेमे को सदमा पहुंचा है. सिंह ने खरसिया से उपचुनाव यह दिखाने के लिए लड़ा था कि उस क्षेत्र में उनका शुक्ल से ज्यादा प्रभाव है.

पार्टी को चुस्त-दुरुस्त बनाने का काम मुख्यतः उत्तरी राज्यों में ही हो रहा है. केंद्रीय ग्रामीण पुनर्रचना राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी दक्षिण में पार्टी को दुरुस्त करने की लड़ाई अकेले जारी रखे हुए हैं. वहां पिछले एक साल से कोई पार्टी पदाधिकारी ही नहीं है. उन्होंने संगठन के पुनर्गठन के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आंध्र प्रदेश में भी राजीव ने कई वरिष्ठ कांग्रेसियों की इस अपील को नकार दिया कि केंद्रीय उद्योगमंत्री जे. वेंगल राव को प्रदेश इंका प्रमुख पद से हटाया जाए.

महाराष्ट्र और गुजरात में भी राजीव पता नहीं क्यों पार्टी में फेरबदल करने से डरते हैं. इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री प्रदेश इंका समितियों के पुनर्गठन के लिए अनुरोध करते रहे हैं. गुजरात में अहमद पटेल का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ़ा जा सका है. गोधरा में चुनावी हार के बाद पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था.

प्रधानमंत्री अब अपनी पार्टी को कई मोर्चों पर सक्रिय करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कभी-कभी इनमें विरोधाभास और टकराव दिखने लगता है. पार्टी से जैसे कामकाज की वे अपेक्षा करते हैं, वैसा नहीं हो पा रहा है. लिहाजा, अगले साल भी आत्म-विश्लेषणों और राजनैतिक विचार गोष्ठियों का सिलसिला जारी रहेगा. पार्टी के चरमराते ढांचे में उत्साह की लहर संचारित नहीं होने की एक मुख्य वजह यह है कि नीचे तक यह धारणा पुष्ट होती गई है कि इसका नेतृत्व भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लीपापोती में लिप्त है. यह धारणा पंडिताऊ विश्लेषणों से शायद ही बदल पाएगी. —प्रभु चावला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नौकरशाही

बेमानी तरक्कियां

दक्षिण के अफसरों का बोलबाला

किसी भी सक्रिय संगठन की तरह नौकरशाही में भी समय-समय पर रिटायर होने वाले लोगों की जगह भरने के लिए फेरबदल होते रहते हैं. लेकिन एक और स्तर पर राजनैतिक प्रशासन के कर्ताधर्ता उच्चस्तरीय फेरबदल का उपयोग कामकाज के ढंग या प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत देने के लिए करते हैं.

इस बात में संदेह नहीं कि पिछले पखवाड़े सचिव स्तर के कई पदों पर जो नियुक्तियां हुई वे बहुत महत्वपूर्ण थीं. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आर्थिक मामलों वाले विभागों में हुआ. डॉ. एन.के. सेनगुप्त नए राजस्व सचिव बने तो नितिन देसाई मुख्य आर्थिक सलाहकार. वित्त सचिव एस. वेंकिटरमनन का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और उनकी जगह पर बिठाने के लिए किसी को तैयार किया जा रहा होगा. लेकिन क्या ये बदलाव सरकार के सोच में किसी भारी या दीर्घकालिक बदलाव का परिचय देते हैं? इस बारे में लोगों की राय एक नहीं है.

आर्थिक मंत्रालयों के कुछ लोगों का मानना है कि सेनगुप्त और देसाई के आने का मतलब है कि आर्थिक उदारता की नीति और मजबूत होगी. विदेशी गठबंधन के कई मामलों को आसानी से सुलझाने वाले वेंकिटरमनन की मुख्य आर्थिक सलाहकार से अच्छी निभेगी क्योंकि देसाई भी उदारता के पक्षधर हैं. इससे पहले देसाई योजना आयोग में विशेष सचिव थे जहां उन्होंने आयात संबंधी वित्तीय नीति वाली सचिव समिति की अध्यक्षता की थी.

सेनगुप्त के मामले में सरकार ने नाटकीय पलटी खाई. कुछ महीने पहले ही उन्हें विशेष सचिव के पद से हटाकर वापस पश्चिम बंगाल काडर में भेज दिया गया था. सेनगुप्त की काबिलियत में किसी को शक नहीं है लेकिन एकाएक वे सरकार के 'दुलारे' कैसे बन गए, यह सामान्य समझ से परे की बात है.

वित्त मंत्रालय की यह नई टोली एक और अर्थ में भी महत्वपूर्ण है. इसे चुनाव वाले वर्ष का बजट तैयार करना है. वेंकिटरमनन, सेनगुप्त और देसाई की तिकड़ी इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि इनका सोच विकासपरक है. आर्थिक मंत्रालय के एक सचिव ने कहा, "यह माना जा रहा है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान नीति की पुनर्रचना की जरूरत है. उद्योगों पर कुछ अरसे के लिए टैक्स कम करके दीर्घकालिक तेज विकास हासिल किया जा सकता है. संभवतः नई टोली इसी तरीके पर विचार करने जा रही है."

डॉ. एन.के. सेनगुप्त को पहले तो वापस प. बंगाल काडर में भेजा गया और फिर अचानक ही उन्हें राजस्व सचिव बना दिया गया

दूसरे मंत्रालयों में भी बदलाव हुए हैं. सी.जी. सोमैय्या की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जे.ए. कल्याणकृष्णन गृह सचिव बने हैं. बिहार के गृह सचिव आर. श्रीनिवासन केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में, के.सी. शिवरामकृष्णन शहरी विकास मंत्रालय में, पी.वी. कृष्णस्वामी योजना आयोग में सेनगुप्त की जगह पर और मीरा सेठ नागरिक आपूर्ति विभाग में सचिव बनी हैं. खाद्य संसाधन विभाग में पी. मुरारी और पर्यावरण मंत्रालय में के.पी. गीताकृष्णन सचिव बने हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय में मोंटेक सिंह अहलूवालिया का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विशेष सचिव बना दिया गया है.

जे.ए. कल्याणकृष्णन को नया गृह सचिव बनाए जाने से फिर दक्षिण भारतीय लॉबी मजबूत हुई है. फिलहाल नौ सचिवों में छह दक्षिण से हैं

भारतीय प्रशासनिक सेवा की उच्च पदों वाली नियुक्तियों को अक्सर उत्तर-दक्षिण के आधार पर देखा जाता है. नौ नए सचिवों में से छह दक्षिण से हैं, इसलिए दक्षिण भारतीय 'लॉबी' के मजबूत होने के चर्चे जल्दी ही सुनाई पड़ने लग सकते हैं. वैसे यह तो तय ही है कि अभी दक्षिण भारतीय अधिकारियों का पलड़ा भारी है क्योंकि सचिव स्तर के 46 में से 14 पद अभी उनके पास हैं. लेकिन बड़े अफसरों को जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वह है मनमाने ढंग से की जाने वाली नियुक्तियां. इस बार 1955, '57 और '58 के बैच के सारे लोगों को एक ही साथ मिलाकर उनके नामों पर विचार किया गया. इसीलिए 1958 बैच की मीरा सेठ भी 1955 वाले कल्याणकृष्णन और श्रीनिवासन के साथ सचिव बन गईं.

जो चीज आईएएस अधिकारियों को उनके अधिकार के तौर पर मिल जाती है उसके लिए विशेषज्ञ अधिकारी (टेक्नोक्रेट) और दूसरे लोगों को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है. 1980 के दशक के शुरू में वी.डी. कपूर, संतोष सोंधी, वी. कृष्णमूर्ति, लवराज कुमार, पी.के. बसु और एस.एस. मराठे जैसे गैर-आईएएस लोगों ने भारी उद्योग, इस्पात और खान, पेट्रोलियम और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंत्रालयों का कामकाज संभाला. अब ऐसे विशेषज्ञ अधिकारी सिर्फ एकाध मंत्रालय ही संभाल रहे हैं. ऐसे ही एक अवकाशप्राप्त अधिकारी ने शिकायत की कि सचिव स्तर की तरक्कियां ऊटपटांग तरीके से हो रही हैं.

ऐसी ही विसंगतियों के कारण नौकरशाही आज राजीव गांधी के सत्ता में आने के समय से कहीं ज्यादा बदहाल है. यदि यह विचार सिर्फ सचिव पद पर तरक्की पाने से वंचित नौकरशाहों का ही होता तो इसे उनकी कुंठा मानकर रद्द भी किया जा सकता था. लेकिन यह बात तो आज उन कई लोगों ने भी मानी है जिनकी सचिव के रूप में नियुक्ति हो गई है.

—रविंदर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिजोरम

असंतोष और अनिश्चय

राष्ट्रपति शासन लागू, संकट में पड़ गया समझौता

राजीव गांधी ने जितने भी समझौते किए उन सब की त्रासदी यह है कि वे इतने अच्छे थे कि टिक नहीं पाए. मिजोरम समझौता भला अपवाद कैसे रहता! ललदेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) की सरकार के सत्तासीन होने के ठीक 19 महीने बाद 7 सितंबर को वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. यह नौबत इस बहाने आई कि सत्ता दल के आठ विधायकों ने पार्टी से अलग होकर एक नया दल एमएनएफ (डी) बना लिया. उनका मकसद इंका के साथ साझा सरकार बनाना था. लेकिन यह हो न पाया और राज्य फिर से अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया. ऐसे में आइजोल की दीवारों पर इन दिनों चिपकाए गए पोस्टर महत्वपूर्ण हैं. इनमें अपील की गई है, "राजीव हमें वापस जंगलों में लौटने पर मजबूर न करो."

मिजोरम अब चौथा राज्य बन गया है जहां हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया. केंद्र के इस फैसले से ललदेंगा के समर्थक और विरोधी दोनों ही खेमों में रोष फैल गया है. ललदेंगा खुद भी भड़क उठे क्योंकि अपनी सरकार की बरखास्तगी के एक दिन पहले ही वे राज्यपाल हितेश्वर सैकिया से मिले थे और उन्हें बताया था कि वे 14 सितंबर को विश्वास मत हासिल करना चाहेंगे. इससे पहले आठ विधायकों के पाला बदलने के कारण एमएनएफ की सरकार (40 विधायकों के सदन में इसके 25 विधायक थे) अल्पमत में आ गई थी. ललदेंगा को विश्वास था कि केंद्र उनका समर्थन करेगा.

लेकिन केंद्र के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश इंका अध्यक्ष ललथनहवला भी सकते में पड़ गए. कहा जाता है कि एमएनएफ को तोड़ने का कौशल उन्होंने ही किया था. विधानसभा में इंका विधायकों की संख्या 13 है. ललथनहवला ने कहा, "यदि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर अमल किया गया होता तो मेरी सरकार बन जाती."

सैकिया केंद्र की कार्रवाई के बचाव में दलील देते हैं कि किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था. बहरहाल, इंका आलाकमान ने राज्य में सत्ता हथियाने का मौका गंवाकर कइयों को चकित कर दिया है. जाहिर है केंद्र को डर था कि वहां इंका की सरकार बनने दी गई तो राज्य में, जहां दो दशकों की बगावत के बाद शांति लौटी है, कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है. दूसरे वह इसलिए भी हिचक गया क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र ने नगालैंड में पूर्ण बहुमत होते हुए भी विपक्ष की सरकार नहीं बनने दी थी.

एमएनएफ के टूटने के आसार इधर कुछ महीनों से मजबूत हो गए थे. ललदेंगा बताते हैं कि सत्तासीन होने के महीने भर बाद ही उन्हें असंतुष्टों की गतिविधियों की जानकारी हो गई थी. 24 मार्च को ललविया समेत पांच विधायकों ने धमकी दी थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया तो वे इस्तीफा देकर इंका के साथ हो जाएंगे. यहां तक कि उन्होंने यह भी बता दिया था कि वे कौन-से मंत्रालय लेना चाहेंगे. ललदेंगा ने इस 'राजनैतिक ब्लैकमेल' के सामने झुकने से इनकार कर दिया था.

उन्हें संदेह था कि उनका तख्ता पलटने की साजिश चल रही है. इसलिए उन्होंने 29 अगस्त को दो विधायकों पी. सियाम्तियाना और वनललरुइया को पार्टी विरोधी गति-

ललदेंगा (नीचे); और असंतुष्टों के बीच ललविया (सबसे नीचे): बिखराव

प्रशांत पंजियार

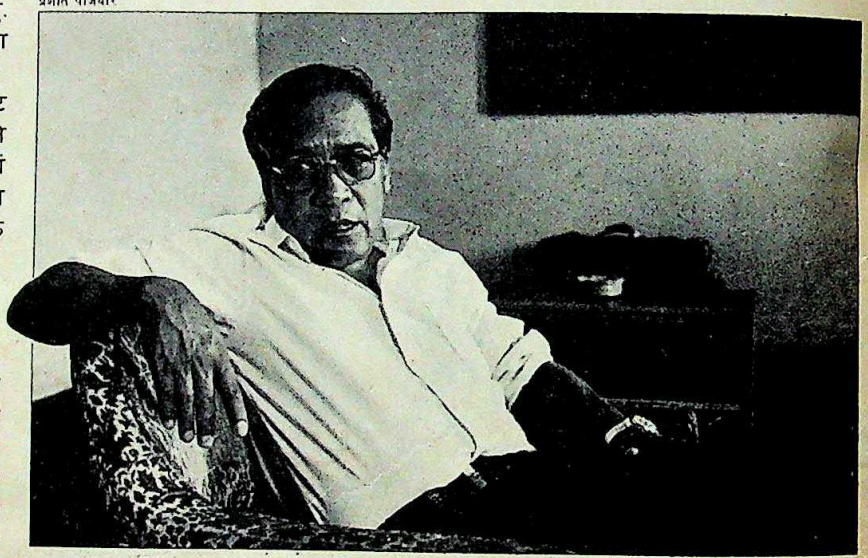

सैबल दास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विधियों के लिए निलंबित कर दिया. ललदेंगा का संदेह कुछ घंटे बाद ही सही साबित हो गया. एमएनएफ के उपाध्यक्ष च्वांग्जुआला के नेतृत्व में आठ विधायकों ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी सौंपी. इस चिट्ठी में उन्होंने एक नए दल मिजो नेशनल फ्रंट (डेमोक्रेसी) बनाने की जानकारी दी. उधर हुए गुट ने इंका के साथ मिलकर सरकार बनाने का इरादा भी तुरंत जाहिर कर दिया.

लेकिन ललदेंगा ने यह घोषणा करके उन्हें

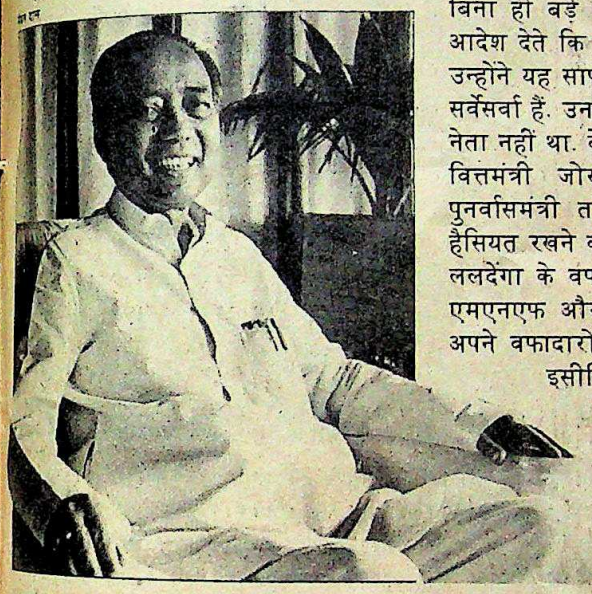

ललथनहवला; और (ऊपर) सैकिया: मतभेद उजागर

प्रशांत पंजियार

चौंका दिया कि केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया है कि केंद्र असंतुष्टों का समर्थन नहीं करेगा. इसने ललथनहवला को आठ विधायकों से यह वायदा करने पर मजबूर कर दिया कि यदि उन्हें सरकार बनाने की मंजूरी नहीं मिली तो वे इंका से इस्तीफा दे देंगे. यह मानते हुए कि पार्टी आलाकमान से उन्हें ऐसा करने की मंजूरी है, वे और आगे बढ़े. उन्होंने बागी विधायकों के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का भी गठन कर लिया.

यह सही है कि एमएनएफ में टूट का फौरी कारण आठ विधायकों की स्वार्थपरता ही है. पर ललदेंगा का निरंकुश रवैया भी एक बड़ा कारण है. वे एमएनएफ को भी उसी ढंग से चला रहे थे जैसे वे भूमिगत मिजो नेशनल आर्मी (एमएनए) को कमांडर की हैसियत से चलाया करते थे. वे पार्टी से सलाह लिए बिना ही बड़े फैसले ले लेते और फिर आदेश देते कि उसे इन्हें मंजूर करना है. उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वे ही सर्वेसर्वा हैं. उनके मंत्रिमंडल में कोई बड़ा नेता नहीं था. वे चाहते भी नहीं थे. सिर्फ वित्तमंत्री जोरमथंगा और राहत व पुनर्वासमंत्री टॉनलुइया ही अपनी कुछ हैसियत रखने वाले मंत्री थे और ये दोनों ललदेंगा के वफादार रहे. ललदेंगा चूंकि एमएनएफ और सरकार दोनों में सिर्फ अपने वफादारों को ही रखना चाहते थे इसीलिए उन्होंने पार्टी के आलाकमान से उन्हें ऐसा करने की मंजूरी है, वे और आगे बढ़े. उन्होंने बागी विधायकों के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का भी गठन कर लिया.

यह सही है कि एमएनएफ में टूट का फौरी कारण आठ विधायकों की स्वार्थपरता ही है. पर ललदेंगा का निरंकुश रवैया भी एक बड़ा कारण है. वे एमएनएफ को भी उसी ढंग से चला रहे थे जैसे वे भूमिगत मिजो नेशनल आर्मी (एमएनए) को कमांडर की हैसियत से चलाया करते थे. वे पार्टी से सलाह लिए बिना ही बड़े फैसले ले लेते और फिर आदेश देते कि उसे इन्हें मंजूर करना है. उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वे ही सर्वेसर्वा हैं. उनके मंत्रिमंडल में कोई बड़ा नेता नहीं था. वे चाहते भी नहीं थे. सिर्फ वित्तमंत्री जोरमथंगा और राहत व पुनर्वासमंत्री टॉनलुइया ही अपनी कुछ हैसियत रखने वाले मंत्री थे और ये दोनों ललदेंगा के वफादार रहे. ललदेंगा चूंकि एमएनएफ और सरकार दोनों में सिर्फ अपने वफादारों को ही रखना चाहते थे इसीलिए उन्होंने पार्टी के चुनाव नहीं करवाए. इसलिए काबिल व्यक्ति ऊपर नहीं आ पाए.

इनमें से कई तो मिजोरम समझौता होने के बाद राष्ट्रीय मुख्यधारा में लौटे लोग थे. ऐसों में एक तो कपदुंगा हैं. वे एमएनए में मेजर थे. उन्हें 11 साल तक जेल में रहना पड़ा था. उन्हें ललदेंगा ने अलग ही रखा. लेकिन जनता उन्हें एक नायक की तरह देखती है जिसने मिजो लोगों के लिए बहुत प्रताड़ना सही है.

ललदेंगा ने बागी जीवन से लौटे कई व्यक्तियों को तो साथ नहीं लिया पर उन्होंने एमएनए के कुछ सहयोगियों को जरूर शामिल किया जो खुलेआम घूमते रहे थे. बिना किसी राजनैतिक हैसियत वाले एक स्कूल अध्यापक ललहलिम्पुई को समाज कल्याणमंत्री बना दिया गया. सैंगुरा सैलो चुनाव के ठीक पहले एमएनएफ में शामिल हुए और उन्हें कानूनमंत्री बना दिया गया. एक मोटर वाहन निरीक्षक लाग्मिंगथंगा को पशुपालनमंत्री बना दिया गया. लेकिन जिस बात ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सचमुच नाराज कर दिया वह थी ललदेंगा के एक करीबी रिश्तेदार, पीपुल्स कान्फ्रेंस के विधायक रम्मावी को एमएनएफ में शामिल कर उन्हें आपूर्तिमंत्री बनाया जाना.

इन संदेहों से भी ललदेंगा की छवि धूमिल हुई है कि उन्होंने जनता की कीमत पर संपत्ति अर्जित की है. यह व्यापक चर्चा का विषय है कि मात्र साढ़े पांच लाख की आबादी वाले राज्य को केंद्र से अनुदान के रूप में मिले 200 करोड़ रुपए कुछ चुनींदा लोगों ने हथिया लिए. मंत्रियों की विलासितापूर्ण जीवन शैली पर उंगली उठाई गई. ललदेंगा खुद भी आइजोल में एक विशाल बंगला बनवा रहे हैं. और इन आरोपों का कोई खंडन नहीं किया गया है कि उन्होंने इसमें सरकारी साधनों का उपयोग किया है. एमएनएफ (डी) के उपाध्यक्ष वनललरुइया पूछते हैं, "बीस साल तक भूमिगत रहने वाले किसी व्यक्ति के पास ऐसा भव्य बंगला बनाने का पैसा कहां से आ गया?"

इस ईसाईबहुल राज्य में ललदेंगा ने जब इस साल मार्च में शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस दुबारा देने के प्रयास किए तब उन्हें चर्च के विरोध का भी सामना करना पड़ा. राज्य में हर महीने शराब की 1.20 लाख से अधिक बोतलों की खपत है.

अब कई पूर्व बागियों, चर्च और विधायकों के गुट का समर्थन खो देने के बाद ललदेंगा वाकई एक बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं. केंद्र ने भी उन्हें एक तरह से खारिज कर दिया है. ऐसे में उनकी मुसीबतें और बढ़ ही गई हैं. वैसे अभी भी उनके पास समय है और चुनावों के पहले वे अपनी छवि फिर से दुरुस्त कर सकते हैं. लेकिन यदि वे ऐसा न कर पाए तो राजनीति के अंधेरे बियाबान में गुम हो सकते हैं और जो सत्ता उन्होंने कड़े संघर्ष के बाद हासिल की थी उसे उनके ही दूसरे साथी हथिया सकते हैं. —रमेश मेनन, आइजोल में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डीडीए

बालू से बनाए गए बसेरे

कालकाजी इलाके में 111 फ्लैटों के लोग मौत के साये में

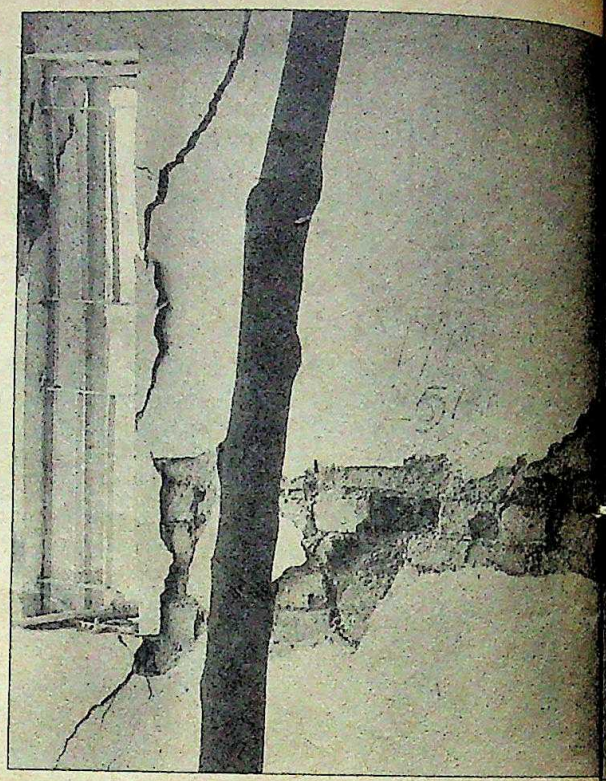

अठारह अगस्त की रात. करीब एक बज रहा था. दिन में तो बारिश ही होती रही थी. दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में डीडीए क्वार्टरों के एक खंड की दीवारों में एकाएक चौड़ी-चौड़ी दरारें दिखने लगी, मानो किसी ने टोना-टोटका कर दिया हो. नींव हिलने से पैरों तले से जमीन धंसने लगी. दरवाजे तो जैसे जाम हो गए. वहां रहने वाले एक बैंक कर्मचारी ओ.पी. अरोड़ा कहते हैं, "कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है, यह समझने में हमें आधा घंटा लग गया." मौत के साये में सैकड़ों लोगों ने रात जागते हुए बिताई. उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है.

धीरे-धीरे पूरी कॉलोनी के अनेक मकानों में हस्तरेखाओं जैसी दरारें नजर आने लगीं. फर्श अजीबोगरीब तरीके से ऊंचे-नीचे हो गए. एक मकान का छज्जा तो झूले की तरह झूलने लगा. लगता था फ्लैट भरभराकर किसी भी वक्त गिर पड़ेंगे. एक हफ्ते के भीतर ही डीडीए ने कालकाजी के 111 फ्लैटों को खतरनाक घोषित कर दिया और उनमें रह रहे करीब 256 परिवारों को घर खाली कर देने के लिए कहा. तत्काल एक सरकारी पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि "इस फ्लैट में आप अपनी जोखिम पर ही रह सकते हैं." डीडीए के एक इंजीनियर डी.पी. सिंह के मुताबिक फ्लैट कच्ची जमीन पर और शायद एक नाले को पाटकर बनाए गए थे. भारी बारिश की वजह से नींव खिसक गई.

इस तरह कालकाजी के सैकड़ों लोगों के लिए डीडीए निर्मित दु:स्वप्न की घड़ियां शुरू हुईं. उसका सबसे पहला शिकार विद्यासागर का मकान हुआ. पहले डीडीए ने उन्हें वैकल्पिक घर मुहैया कराया और फिर उसे भी खाली करने को कह दिया. पिछले हफ्ते विद्यासागर को दुबारा एक दड़बेनुमा मकान में जाने का हुक्म सुना दिया गया.

मकड़जाल में फंसी मक्खी की तरह विद्यासागर अपने पुराने भरभराते मकान में चारों बीमार बच्चों समेत लौट आए. उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था. लेकिन मकान इतनी खस्ता हालत में था कि उन्हें फिर निकलना पड़ा. अब वे डीडीए से मिले एक छोटे-से मकान में रह रहे हैं. 15 दिनों में यह चौथा मकान है. उनका आधा सामान घर में है और आधा सड़क पर. इस कवायद से टूटे विद्यासागर कहते हैं, "वे और कर भी क्या सकते हैं. मैं हर हालत का सामना करने को तैयार हूं."

सात साल पहले जब डीडीए ने ये फ्लैट बनाने शुरू किए थे तो जाहिर है कि उसने जमीन की पूरी जांच-पड़ताल नहीं की या इसके बारे में रिपोर्टों की अनदेखी कर दी. तीन साल के दौरान ज्यादातर फ्लैट भर गए. इस दौरान खास बारिश भी नहीं हुई. सारा रहस्य दबा रहा. इस साल के मानसून ने डीडीए के घटिया काम की कलई खोल दी. ताश के पत्तों की तरह मकान गिरने लगे. वहां के निवासी जब डीडीए उपाध्यक्ष के.एस. बैंस से शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि यह भूकंप की वजह से हुआ है.

इस इलाके के ज्यादातर निवासी दक्षिण दिल्ली में रहने का ख्वाब संजोकर आए थे, भले ही कर्ज उनके सिर चढ़ गया था. लकड़ी की आधुनिक साज-सज्जा, लिनोलियम और झाड़फानूस लगे ये घर अवकाशप्राप्त लोगों के खुशनुमा बसेरे थे. अब ये लोग डरे हुए हैं. धोखाधड़ी करने वाली सरकारी एजेंसियों के खिलाफ उन्हें कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं. एनसीईआरटी के जनसंपर्क अधिकारी और यहां एक फ्लैट के मालिक टी.आर शर्मा कहते हैं, "अफसोस कि ऐसे घटिया मकान हमारे हवाले किए गए, पर एक ईमानदार अफसर के पास डीडीए का मकान खरीदने के सिवा दूसरा उपाय भी क्या है?"

एक दंपती ने तो अपने बच्चे को एक रिश्तेदार के यहां इसलिए छोड़ रखा है कि रात को न जाने कब उन्हें भागना पड़ जाए. दूसरे लोग धीरे-धीरे चौड़ी होती दरारों के डर से सोने के लिए एक से दूसरे कमरे में भागते-फिरते हैं. महिलाएं पूरी रात बार-बार उठकर छत को ताकती हैं. अनेक पुरुषों ने तो काम पर जाना भी बंद कर दिया है. उन्हें भरोसा नहीं कि लौटने पर 'मकान मिलेगा या स्मारक'. उनकी हताशा बढ़ती जा रही है. अरोड़ा कहते हैं, "साथ वाला मकान गिरते ही हम भी भाग लेंगे."

दो दशक पहले डीडीए का गठन मध्यमवर्ग को बढ़िया मकान मुहैया कराने के लिए किया गया था. दुनिया की सबसे बड़ी इस विकास एजेंसी ने जल्द ही पूरे शहर में अपने पांव पसार लिए. ज्यों-ज्यों मांग बढ़ती गई, घटिया मकान बनते गए. इसका पिछला रिकार्ड तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

हाल ही में साकेत के नजदीक डीडीए की एक कॉलोनी में पीलिया के कई मामले सामने आए. पता चला कि डीडीए ने पीने के पानी और सीवर पाइपों को मिला दिया था. फिर, विकासपुरी के कुछ फ्लैट भी भरभराकर गिर गए. सबसे खस्ता हालत तो किशनगंज कॉलोनी के डीडीए फ्लैटों की थी. उनकी नींव का ही कोई अता-पता न था. डीडीए के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यशवंत सिंह नेगी

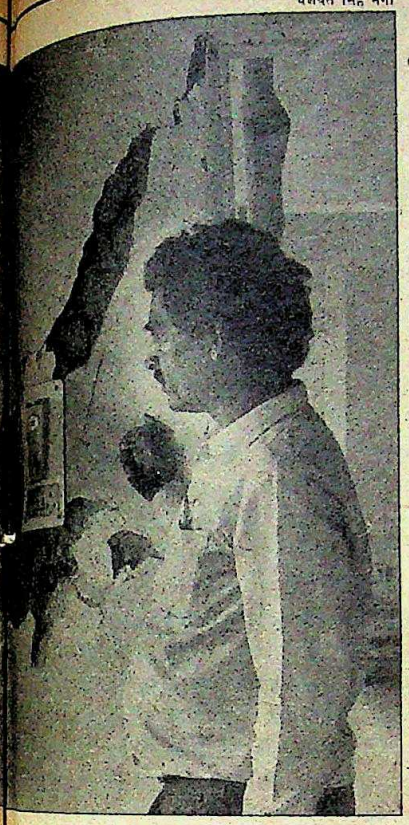

यशवंत सिंह नेगी

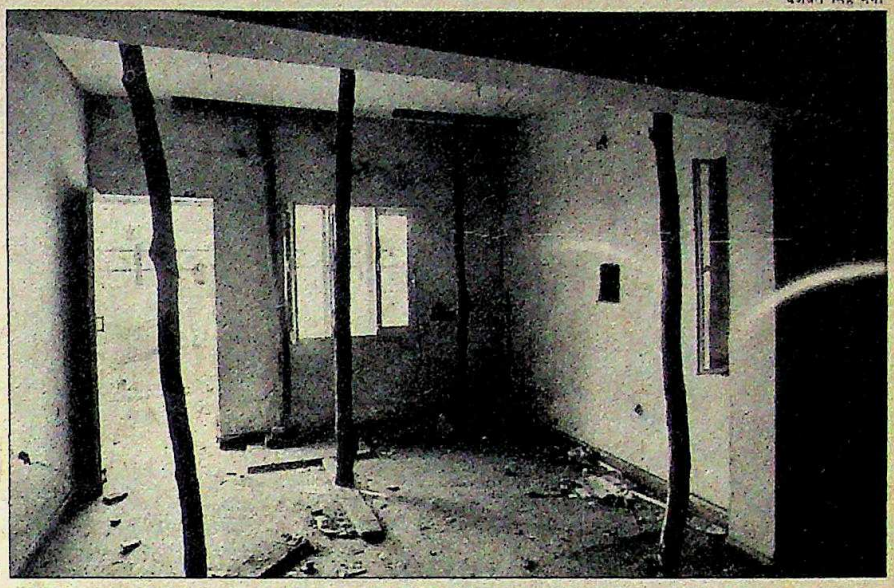

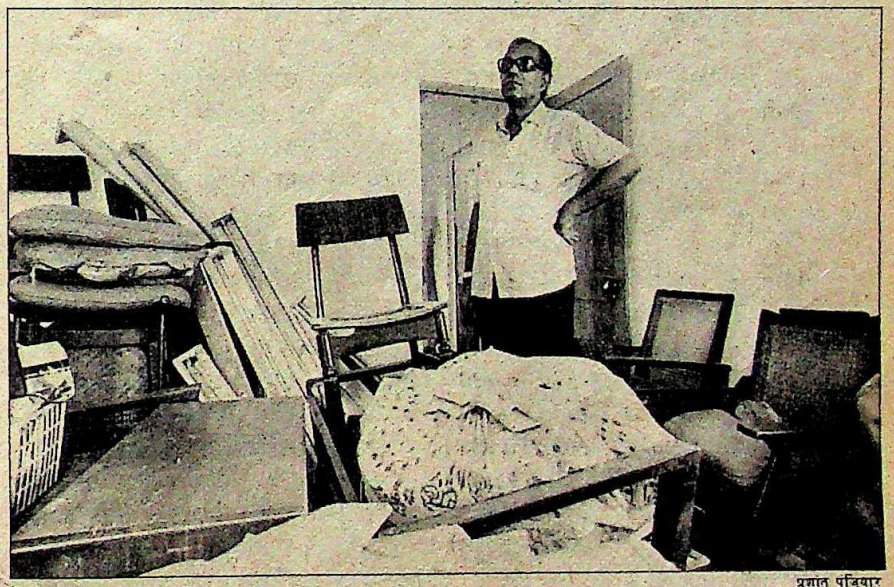

प्रशांत पंजियार

(ऊपर बाएं से दाएं) डीडीए का एक ख़स्ताहाल मकान; लकड़ी के खंभे के सहारे टिकी छत; और (नीचे) अपने नए मकान में एस.आर. गुप्ता: सशंकित

तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रेम कुमार को भी मानना पड़ा था कि ये 'मौत के फंदे' हैं. बैंस को पदभार संभाले एक महीना ही हुआ है. कालकाजी का मामला उनकी अग्निपरीक्षा है.

उम्मीद के मुताबिक डीडीए ने एक उच्च-स्तरीय जांच समिति की घोषणा की है. लेकिन उसकी कछुए की गति से कोई मतलब हल होता नहीं लगता. लोगों की जरूरत तात्कालिक है. एस.आर. गुप्ता, जिनका पहले तल्ले का फ्लैट सीढ़ियों से एकदम अलग हो गया, कहते हैं, "सुबह मुझे अजीब-सा लगता है कि मैं क्यों उठा. कम-से-कम सोए हुए मुझे तनाव तो नहीं रहता."

यहां के निवासियों का जांच समिति में भरोसा नहीं है. उनको अंदेशा है कि जमीन परीक्षण में देरी इसीलिए की जा रही है ताकि जलस्तर नीचे चला जाए. यहां तक कि डीडीए का एक आदमी तथाकथित निष्पक्ष समिति की बैठकों में शामिल रहता है. लोगों को अंदेशा है कि डीडीए चालू तरीके से मरम्मत का काम निबटा देगी.

खतरे वाले 111 घरों में से करीब 30 को ही ठीकठाक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. बाकियों को जनता फ्लैट या दूर कहीं कोठरियां देने की पेशकश की गई है. 55 साल की उम्र में मकान मालिक बन पाए और विकलांग एस.के. वर्मा का सवाल है, "हमारे बच्चों का क्या होगा?" मकान बदलना आसान नहीं, भले ही बैंस इसके लिए 500 रु. की पेशकश कर रहे हैं. नए टेलीफोन के लिए आवेदन करना, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना, नया बैंक खाता खोलना और बस वगैरह भी तो झंझट हैं.

पहली बार लोगों के संगठित होने के संकेत नजर आ रहे हैं. अनेक लोगों ने अभी वहां से न हटने की ठान ली है. एक निवासी ने कहा है, "मुझे तंबू में रहना मंजूर है. अपने को डीडीए के हवाले करने के बजाय मैं अपने फ्लैट के सामने मरना पसंद करूंगा." लोगों ने अपने मामले के लिए एक वकील की सेवाएं भी ली हैं. नागरिक अधिकारों के पक्षधर एच.डी. शौरी कहते हैं, "उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही चाहिए. और अपनी नाराजगी का इजहार भी करना चाहिए." उनका मानना है कि लोग समान वैकल्पिक आवास के साथ अपनी परेशानियों और मानसिक तनाव के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं. वे कहते हैं, "सामूहिक कार्रवाई से ही डीडीए रास्ते पर आएगी."

बहरहाल, इस सब में वक्त लगेगा. खुद डीडीए की जांच में कई हफ्ते लगेंगे. कई वर्षों की मरम्मत के बाद ही 'घर' फिर से रहने के काबिल हो पाएंगे. लेकिन सवाल यह है कि इस बीच लोगों का ठौर-ठिकाना क्या होगा. अगली बारिश हुई तो कालकाजी वालों को अपने मकानों का हुलिया पता करना मुश्किल हो जाएगा.

—सिमरन भार्गव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

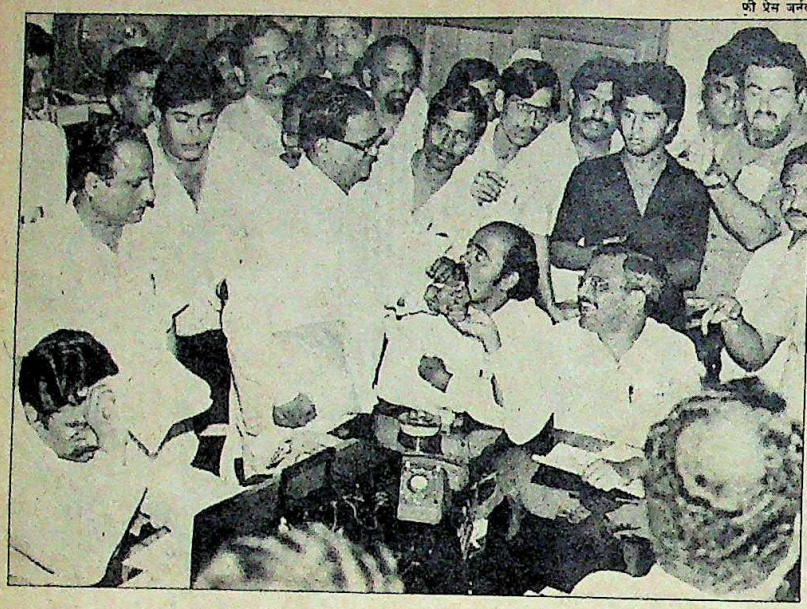

पी प्रेस जर्नल

(एकदम दाएं बैठे) रावते; (उनके पीछे दाढ़ी वाले) तीरंदाज: भंडाफोड़

महाराष्ट्र

धमकी भरा टेप

शिवसेना के नेता मुसीबत में

यह किसी हिंदी फिल्म की पटकथा का ही अंश लगता है. पारसियों के 'नवरोज' (नए साल) को एक नगर निगम पार्षद के घर बधाई स्वरूप मिठाई का एक डिब्बा आता है. डिब्बे में बरफियों के नीचे एक कैसेट रखा हुआ है. हैरान पार्षद कैसेट चलाते हैं, और कैसेट सुनते ही छुट्टी का उनका मूड खराब हो जाता है.

कैसेट में गूंजती आवाज देश के सबसे धनी-मानी, 800 करोड़ रु. सालाना बजट वाली बंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष की है. लेकिन यह आवाज बंबई को एक 'बेहतर नगर बनाने' जैसे शाश्वत संदेश नहीं दे रही थी बल्कि कुछ व्यापारियों को पार्टी कोष में मोटा चंदा देने के लिए धमका रही थी. और शेखी बघारते हुए उन्हें बता रही थी कि किस तरह उनकी पार्टी ने अहमदाबाद और भिवंडी में हुए सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोगों को कत्ल करवाया.

यह आवाज थी नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष दिवाकर रावते की. और मिठाई के साथ कैसेट का उपहार पाने वाले थे दादर पारसी कॉलोनी से निर्दलीय पार्षद रुस्तम तीरंदाज. वे कहते हैं, "मैंने रावते की आवाज तो तुरंत पहचान ली लेकिन एक हफ्ते तक मैं चुप ही रहा क्योंकि मैं तय नहीं कर पा रहा था कि टेप उजागर करने पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी. लेकिन एक सितंबर को निगम की एक बैठक में जब रावते ने निगम के अधिकारियों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया तो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने टेप का राज जाहिर कर दिया." इस पर सदन में हड़कंप मच गया और तीरंदाज से सबूत पेश करने के लिए कहा गया. कुछ घंटे बाद नेता लोग टेप सुनने के लिए महापौर चंद्रकांत पडवाल के कक्ष में आ जुटे. मौके पर मौजूदा पार्षदों और पत्रकारों का कहना है कि पडवाल और रावते दोनों ने ही माना कि यह आवाज रावते की ही है.

शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने एक अखबार में दिए इंटरव्यू में रावते की बातें टेप करने को 'एक ओछी हरकत' करार दिया. पडवाल ने तो यह कहकर मामले को दरकिनार कर दिया कि नगर निगम को तीरंदाज के टेप से कोई सरोकार नहीं क्योंकि नागरिक सुविधाओं का कोई मुद्दा इससे नहीं जुड़ा है. लेकिन राज्य सरकार और खुफिया ब्यूरो रावते के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित बयानों की पड़ताल में जुट गए. इस पर शिवसेना नेताओं ने तुरंत पैंतरा बदल लिया. पूरे कांड से बौखलाए रावते के पास संबंधित हर सवाल का एक ही सपाट जवाब था 'कोई टिप्पणी नहीं'.

हफ्ते भर बाद पूर्व महापौर छगन भुजबल ने इंका पार्षद देवचंद्र गाला और एक भवन-निर्माता के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का टेप पेश करके इसका जवाब देने की कोशिश की. यह टेप गाला और उनके परिवार के आधिपत्य वाली संपत्ति के बदले भवन निर्माता द्वारा उन्हें दी जाने वाली मुआवजे की रकम के विवाद से संबंधित था. गाला ने भवन निर्माता से पैसा ऐंठने का झूठा आरोप लगाने के लिए भुजबल पर मुकदमा चलाने की धमकी भी दी. लेकिन भुजबल का कहना था कि वे इंका पार्षदों के ऐसे ही 13 और टेप पेश करने को तैयार हैं.

लेकिन आरोपों-प्रत्यारोपों का यह गुलगपाड़ा रावते के विस्फोटक बयानों को दबा नहीं पाया. छोटे गुजराती व्यवसायियों द्वारा पार्टी को दिए जा रहे 5,000 रु. के चंदे से नाखुश रावते ने उन्हें बुरी तरह फटकारा था. उसी टेप के कुछ अंश: "तुम्हारे लोगों (बाकी व्यवसायियों) की जान बचाने के लिए मैंने खुद तलवार हाथ में लेकर भिवंडी में मुसलमानों को कत्ल किया. फिर भी आप नहीं जानते कि दिवाकर रावते कौन है? आप गुजरातियों को मैंने अपने सिर-माथे पर बिठाया... एक दंगे में हमने 300 मुसलमानों को कत्ल किया जिसे आपके व्यापारियों ने भी देखा. अब तक आप क्या देखते रहे. मैं गुंडा नहीं हूं, लेकिन हमारे नेताओं ने वक्त पड़ने पर हमें हथियार उठाना भी सिखाया है." भ्रष्ट तौर-तरीकों के लिए कुख्यात निगम में रावते द्वारा रकम ऐंठने की कथित कोशिश से ज्यादा दंगों में शिवसेना की भूमिका के बारे में उनके उद्गारों से ज्यादा बावेला मचा.

शिवसेना की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई. रावते प्रकरण के साथ ही शिवसेना के पार्षद खिम बहादुर थापा और पुलिस के बीच गोलीबारी की घटना भी हो गई. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में नजरबंदी के दौरान जेल से पार्षद का चुनाव जीतने वाले थापा और उनके भाई को कत्ल के एक मामले में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दस्ता रात में उनके घर गया था. थापा बंधु तो छत से कूदकर भाग गए पर उनके साथियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाकर एक सब-इंस्पेक्टर और हवलदार को घायल कर दिया. इस घटना से यह तथ्य शिद्दत से उभर आया कि भ्रष्टाचार और हिंसा किस तरह शिवसेना की कार्यशैली का अभिन्न अंग बन गई है. अहम सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार कोई सख्त कार्रवाई करेगी या इंका के नेता पहले की तरह इस बार भी राजनैतिक समझौता करके खामोश बैठ जाएंगे.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार

त्रासदी में तमाशा

राजनैतिक रंगत देने की कोशिशें

राजनीति हर चीज पर हावी होने लगी है चाहे वह भूकंप जैसी त्रासदी ही क्यों न हो. 21 अगस्त को आए भूकंप के झटकों से जिन हजारों लोगों का जीवन तहसनहस हो गया, वे अभी सदमे से उबर भी न पाए थे कि राजनैतिक दलों और गुटों के बीच आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया. पखवाड़े भर की इस उखाड़-पछाड़ से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है सात महीने पुरानी भागवत झा आजाद सरकार को.

राज्य सरकार भूकंप से हुई क्षति को कम से कम बताने में जुटी थी तो असंतुष्ट इंकाई और विपक्षी नेता उस पर असंवेदनशीलता, निकम्मेपन और राहत कार्यों में सुस्ती बरतने के आरोप लगा रहे थे. राज्य के सर्वाधिक प्रभावित चार उत्तरी जिलों के दौरे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और इंका सांसद जगन्नाथ मिश्र ने आरोप लगाया, "सरकार परिस्थिति के अनुकूल काम करने में नाकाम रही है." इसके जवाब में सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भूकंप के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है.

राजनैतिक सरगर्मियां भूकंप के 24 घंटे बाद तब शुरू हुईं जब प्रधानमंत्री ने राज्य के अपने दौरे में प्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस विपदा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है. इस बयान ने विपक्षी दलों को तो भड़काया ही, असंतुष्ट इंकाइयों को भी नाराज कर दिया. असंतुष्टों ने आरोप लगाया कि आजाद ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया है. आजाद ने स्वीकार किया, "इस हमले से हमारा मनोबल तो नहीं टूटा है लेकिन ठेस जरूर पहुंची है."

विपक्षी दलों की निगाहें तो अगले साल संभावित आम चुनावों पर थीं जबकि असंतुष्ट इंकाई आजाद की विदाई चाहते थे. त्रासदी के तुरंत बाद असंतुष्टों ने पूर्व मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक बैठक की और प्रधानमंत्री सहायता कोष में योगदान करने का फैसला किया.

इसके बाद और तमाशे भी हुए. जब राज्य सरकार ने इंका विधायकों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में योगदान करने को कहा तो प्रदेश इंका अध्यक्ष तारिक अनवर ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपना पैसा बिहार प्रदेश इंका समिति सहायता कोष में जमा कराएं.

इस बीच इंका आलाकमान के पास असंतुष्ट विधायकों के शिकायती खतों का तांता लग गया कि राज्य सरकार का राहत कार्य बिलकुल अपर्याप्त है. शिकायत करने वालों में अखिल भारतीय इंका समिति के डॉक्टर सेल के अध्यक्ष व सांसद सी.पी. ठाकुर और तारिक अनवर भी थे. हालात की गंभीरता को समझते हुए राजीव ने दोनों धड़ों को आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री आजाद

कि वे राहत कार्यों की जांच के लिए राज्य का दुबारा दौरा करेंगे.

चौतरफा हमलों के जवाब में चार मंत्रियों और आठ पार्टी विधायकों ने एक बयान जारी कर जगन्नाथ मिश्र पर राहत कार्यों को नाकाम करने का आरोप लगाया. लेकिन इस बयानबाजी का उलटा ही नतीजा निकला. 61 विधायक, जिनमें ज्यादातर बिंदेश्वरी दुबे के समर्थक थे, खुलकर मिश्र के समर्थन में आ गए. वफादार धड़े को एक और सदमा तब लगा जब मिश्र के भतीजे और राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकीमंत्री अमरेंद्र मिश्र ने इस्तीफे की धमकी दे डाली.

उधर विपक्ष अपने ही द्वंद्वों से घिरा था. भूकंप पीड़ितों की मदद की उसकी योजना कभी अमल में न लाई जा सकी क्योंकि इसके नेता आपसी टांग खिंचाई में ही व्यस्त थे. यहां तक कि विपक्ष के आला नेताओं जनमोर्चा के वी.पी. सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामराव, भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, लोकदल अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा, जपा नेता चंद्रशेखर आदि के दौरे इस त्रासदी का महज राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश ही लगे. इन नेताओं ने विपक्षी सहायता समिति गठित तो की, लेकिन इस समिति का नेता कौन हो इस पर आपस में सहमति नहीं हो पाई. आखिरकार विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल लोकदल के नेता लालू प्रसाद यादव ने एक समानांतर सहायता समिति गठित की है. इससे आजाद को सर्वदलीय सहायता समिति की मांग को ठुकराने का अच्छा बहाना मिल गया, "हम उन लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हैं जो इस विपदा को भी राजनैतिक रंग दे रहे हैं."

इस आपसी तू तू मैं मैं और स्थिति का राजनैतिक फायदा उठाने की ताक में बैठे नेताओं में से किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि इस त्रासदी से त्रस्त लोगों की सुध ले सके जो आज भी खुले आसमान के नीचे न्यूनतम सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं.

—फरजंद अहमद

प्रभात पंजियार

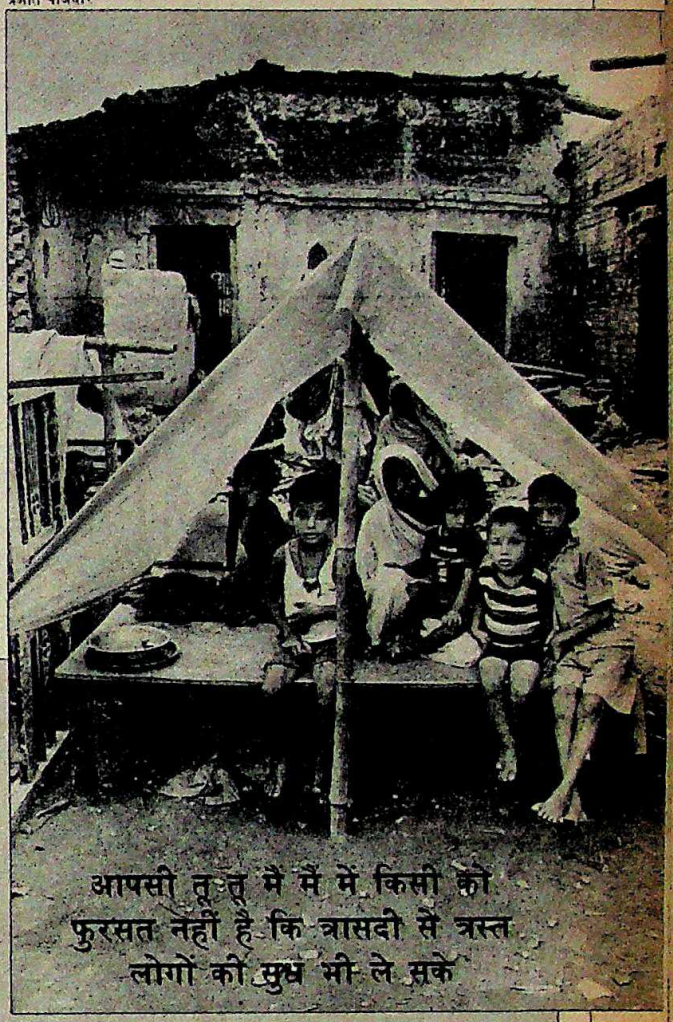

आपसी तू तू मैं मैं में किसी को फुरसत नहीं है कि त्रासदी से त्रस्त लोगों की सुध भी ले सके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एनसीपीए

मंजूरी पर विवाद

रिहायशी इमारत की योजना

संस्कृति वस्तुतः एक नाजुक मामला है. यह अकाट्य सचाई टाटा घराने से छिपी नहीं है. उसे अपने करोड़ों के कारोबार में शायद इतने विवादों का सामना नहीं करना पड़ा होगा जितना बंबई के मंचीय कलाओं के राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीए) के विकास में करना पड़ा है. नरीमन प्वाइंट पर इस केंद्र के परिसर में एक सुसज्जित रिहायशी इमारत के निर्माण की महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी से एक बार फिर विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है.

पुरानी है जितना यह संगठन. लेकिन वर्षों के विवाद और मुकदमेबाजी के बाद सरकार ने अब जाकर इसे हरी झंडी दिखाई है. राष्ट्रीय केंद्र की शुरुआत सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने की. दिसंबर 1969 में इंदिरा गांधी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था. सितंबर 1974 में यह नरीमन प्वाइंट पर स्थानांतरित हो गया. लगभग रोजाना मंचीय कला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले और अमूमन कार्यशालाएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र के पास रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए पैसे की कमी हो गई है. प्रस्तावित रिहायशी भवन बेचने से मिली रकम पर 3 करोड़ रु. सालाना के ब्याज से वह अब अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाया करेगा.

राष्ट्रीय केंद्र के अध्यक्ष जे.जे. भाभा कहते हैं, "सारी दुनिया की सरकारें सांस्कृतिक संस्थानों की मदद करती हैं. लेकिन हमें पता है कि हम अपनी सरकार से ऐसी मांगें नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं दूसरी हैं. इसलिए हमने दक्षिण बंबई में संपन्न लोगों को फ्लैट की बिक्री करके धन जुटाने की सोची."

प्रस्तावित रिहायशी भवन बेचने से मिली रकम पर सालाना ब्याज से केंद्र रोजमर्रे का खर्च निकालना चाहता है

चंद्रशेखर प्रभु (ऊपर); और टाटा थिएटर: विरोध की लहर

सांस्कृतिक केंद्र में रिहायशी इमारत की प्रस्तावित योजना के विरोध की अगुआई युवा इंका विधायक चंद्रशेखर प्रभु कर रहे हैं. सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र नरीमन प्वाइंट पर रिहायशी भवन बनाने की अनुमति दिए जाने पर उन्होंने पिछले महीने बंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (बीएमआरडीए) को एक विरोधपत्र दिया. इन सुसज्जित फ्लैटों की बिक्री से 55 करोड़ रु. के मुनाफे की उम्मीद है, जिसमें यह राष्ट्रीय केंद्र और राज्य सरकार बराबर के भागीदार होंगे. लेकिन प्रभु विरोध व्यक्त करते हुए कहते हैं, "जब पूरी बंबई में पानी सरीखी मूलभूत सुविधाओं का अकाल हो, दक्षिणी हिस्से पर गगनचुंबी भवन बनाने की अनुमति देना जुर्म है."

राज्य सरकार से उपहार में मिले आठ एकड़ के प्लॉट में इमारत बनाने की राष्ट्रीय केंद्र की प्रस्तावित योजना करीब उतनी ही

राष्ट्रीय केंद्र को नरीमन प्वाइंट इलाके के नए नियमों की वजह से पहले एक कार्यालय भवन बनाने की योजना छोड़नी पड़ी. इसके बाद एक होटल बनाने की योजना सीमेंट कांड में इस केंद्र का नाम घसीटे जाने से खटाई में पड़ गई. 1975 में इस प्रकरण की वजह से ही अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था. इसके बाद बंबई बचाओ समिति ने बंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी. अदालत ने आखिर कुछ शर्तों पर राष्ट्रीय केंद्र को इमारत बनाने की अनुमति दे दी. इसमें निर्माण कानून के तहत जिस 3 लाख वर्ग फुट जमीन पर उसे इमारत बनाने की इजाजत मिली उसमें से 60,000 वर्ग फुट उसे अपनी गतिविधियों के लिए रखने का प्रावधान है. राज्य के शहरी विकासमंत्री इशाक जामखानवाला कहते हैं, "अब यह सारी हाय-तौबा गैरजरूरी है क्योंकि सरकार ने हाईकोर्ट फैसले के मद्देनजर ही यह मंजूरी दी है. इस योजना से कम-से-कम 27 करोड़ रु. हासिल होंगे."

राष्ट्रीय केंद्र पर ये भी आरोप हैं कि सरकार से उपहार में मिली जमीन पर उसने 'आभिजात्य संस्कृति' का अड्डा कायम कर रखा है. भारतीय राष्ट्रीय नाट्यशाला के महासचिव दामू झवेरी को शिकायत है कि राष्ट्रीय केंद्र का आलीशान नाट्यगृह अमूमन किराए पर नहीं दिया जाता. वे इस केंद्र को ऐसे समय सरकारी मदद देने पर एतराज उठाते हैं जबकि शहर के दूसरे सांस्कृतिक संस्थान पैसे की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं.

लेकिन राष्ट्रीय केंद्र को एक अप्रत्याशित जगह से समर्थन मिला. फिल्म और नाट्य अभिनेता तथा वामपंथी भारतीय जन-नाट्य संघ के अध्यक्ष ए.के. हंगल कहते हैं, "एनसीपीए ने शहर के सांस्कृतिक जीवन में योगदान दिया है. बंबई की ज्यादातर नाट्यशालाएं अभिजातवर्गीय हैं, इसीलिए अहम बात यह है कि वे किस तरह के नाटक खेल रहे हैं."

राष्ट्रीय केंद्र के अवैतनिक निदेशक और मराठी के जाने-माने लेखक पु.ल. देशपांडे कहते हैं, "देश की एक भी भाषा नहीं बची जिसमें हमने नाटक न खेले हों. यदि आप हमारे मासिक कार्यक्रमों पर नजर डालें तो उनमें कलाकारों और नाटक, नृत्य, संगीत, सिनेमा, फोटोग्राफी और चित्रकारी हर तरह के कलाप्रेमियों के लिए कुछ न कुछ रहता है." करीब 20 वर्षों की अपनी जिंदगी में राष्ट्रीय केंद्र ने धीरे-धीरे शहर के सांस्कृतिक जीवन में अपनी अहम जगह बना ली है. हालांकि यह सदाबहार संस्था विवादों की महामारी का शिकार है पर लंबे अरसे से रुकी इमारत योजना पूरी हो जाने से इसकी वित्तीय हालत सुधर जाएगी और यह अपने विकास कार्यक्रमों के आखिरी चरण को पूरा कर लेगी. —एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अजिताभ बच्चन

दाग धोने का नाटक

आप्रवासी भारतीय का दर्जा देकर मामला रफादफा किया गया

कहना मुश्किल है कि यह हकीकत है या फसाना. पिछले पखवाड़े अजिताभ बच्चन अपने खिलाफ उठे तमाम बवंडरों के थमने के बाद ठीक उसी तरह विजेता की मुद्रा में दिखे जैसे उनके भाई अमिताभ अपनी फिल्मों के आखिर में दिखते हैं—तमाम खलनायकों को परास्त कर देने वाले धीरोदात्त नायक के रूप में. प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले पखवाड़े 66 पन्नों के अपने एक आदेश में उन्हें पाक-साफ करार दे दिया.

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक कृष्णकांत ने लगभग एक साल तक उनके मामले की बड़े गुपचुप और रहस्यमय तरीके से अर्ध-न्यायिक जांच की. और अंततः अजिताभ को 28 फरवरी 1986 से आप्रवासी भारतीय ठहरा दिया. यानी अब अजिताभ विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) के तीखे पंजों से बेफिक्र होकर विदेशी मुद्रा का लेन-देन कर सकेंगे. मगर प्रवर्तन निदेशालय ने कई सवाल अनुत्तरित ही छोड़ दिए हैं. अजिताभ के खिलाफ आरोप यह था कि एक भारतीय नागरिक होते हुए वे विदेशों में धन जमा कर रहे हैं. इस आरोप के पक्ष में कई पुख्ता-सबूत भी थे जिनकी भारत और विदेशों में पुष्टि हो चुकी है. ये सबूत थे:—

- जेनेवा से 95 किलोमीटर दूर, मांट्रेयू में उनके नाम से 45 लाख रुपए में खरीदे गए फ्लैट की मिल्कियत के दस्तावेज.
- 85 लाख रुपए की पूंजी वाली स्विस दवा कंपनी आर्कोलैब के 50 फीसदी शेयरों की मिल्कियत.
- तकरीबन 2.72 करोड़ रुपए की एक पुरानी स्विस कंपनी आर्कोफार्मा को आर्कोलैब द्वारा खरीदे जाने की रजिस्ट्री के कागजात. यह खरीद-बिक्री 1 जुलाई 1987 को होनी थी.
- बंबई की पांच कंपनियों में साझेदारी और इनके निदेशक मंडल की सदस्यता.
- बंबई में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ दो साझे खाते.
- पासपोर्ट नवीकरण की अर्जी में संदर्भ और निवास के लिए बंबई निवास के अपने पतों का उल्लेख.
- भारतीय प्रवासी की हैसियत से हासिल विदेश भ्रमण योजना के कागजात.

किएटिव आई

प्रवर्तन निदेशालय ने असुविधाजनक तथ्यों को नजरअंदाज तो किया ही, मामले की तह तक जाने की भी जुर्रत नहीं की

- व्यापारिक दौरे और पर्यटन के लिए भरे गए वीसा दस्तावेज.
- स्विस अधिकारियों द्वारा प्रवासी वीसा देने से इनकार, जिसके बिना स्विट्जरलैंड में नौकरी करना नामुमकिन है.
- पासपोर्ट जिसमें लगातार तीन महीने तक स्विट्जरलैंड में रहने का कोई जिक्र नहीं.

इन सारे दस्तावेजी सबूतों के जवाब में अजिताभ के पास तीन पन्नों का एक पत्र था जिसमें आर्कोफार्मा ने उन्हें 10,000 फ्रांक सालाना (तकरीबन 9.1 लाख रुपए) पर सलाहकार की नौकरी देने का प्रस्ताव किया था. कंपनी का यह प्रस्ताव पत्र 28 फरवरी, 1986 को जारी किया गया और अजिताभ ने उसे उसी दिन स्वीकार भी कर लिया था. यह प्रस्ताव पत्र वैसे तो कोई खास अहमियत नहीं रखता था पर इसमें दर्ज अजिताभ और आर्कोफार्मा के मालिकों की 1984 के बाद से हुई बैठकों की कार्यवाही के ब्यौरे इसे अहम बनाते हैं.

आप्रवासी भारतीय होने के अजिताभ के दावे को भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से पुष्ट किया उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं. मई 1987 में अजिताभ ने बंबई के विनिमय नियंत्रक से अनुरोध किया था कि जिन भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडलों में वे शामिल हैं उनमें उन्हें आप्रवासी भारतीय की हैसियत दी जाए और उनके शेयर भी उसी श्रेणी में तब्दील कर दिए जाएं. उनके खिलाफ चल रही जांच के बावजूद जनवरी-फरवरी 1988 में चार अलग-अलग आदेशों के जरिये उन्हें यह दर्जा दे दिया गया. इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें यह दर्जा 1 अप्रैल 1986 की तारीख से दिया गया, यानी उनके स्विस फ्लैट की रजिस्ट्री से तीन दिन पहले की तारीख से.

मांट्रेयू की वह इमारत जिसकी तीसरी मंजिल का एक फ्लैट अजिताभ बच्चन ने खरीदा

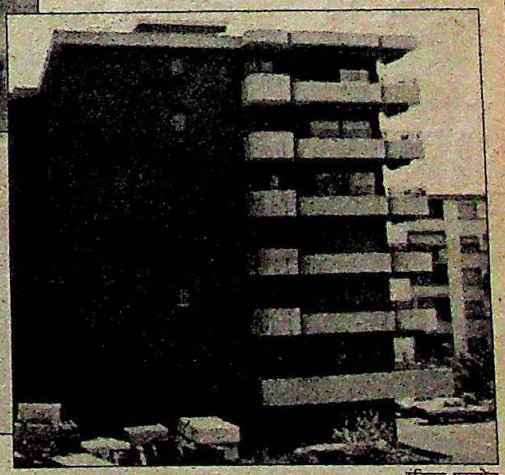

इंडियन एक्सप्रेस

प्रवर्तन निदेशालय ने अजिताभ के लिए असुविधाजनक तथ्यों को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि मामले की तह तक जाने की भी जुर्रत नहीं की. पहली बात तो यह कि इसने आर्कोफार्मा के साथ अजिताभ के संबंधों की गहरी तहकीकात करने की जरूरत नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समझी. उसने आर्कोफार्मा और अजिताभ के व्यापारिक संबंधों पर दोनों के बयानों से ही संतोष कर लिया. भारत में तैनात स्विस अधिकारियों से पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं समझी गई. कार्य परमिट के लिए स्विस अधिकारियों को जून '86 में दी गई अर्जी में अजिताभ ने यह दावा किया है कि उनके पास आर्कोलैब के 50 फीसदी शेयर हैं. अर्जी में उन्होंने अपने निवास के तौर पर ब्रुसेल्स का पता दिया था.

फिर, अजिताभ के स्विस फ्लैट और आर्कोफार्मा में उनकी नौकरी के बारे में निदेशालय को सारी सूचनाएं देने वाले आर्कोफार्मा के प्रमुख साझेदार कोवाक्स ने शुरू में कहा था कि अजिताभ का "आर्कोफार्मा से कोई संबंध नहीं है." (देखिए इंडिया टुडे, 15 अगस्त 1987). साफ है कि सौदा उन न्यासियों ने किया था जो स्विस गोपनीयता कानून की आड़ में बच गए हैं.

अजिताभ को वहां नौकरी शुरू करने के बाद से नियमित रूप से भी तनख्वाह मिलती रही हो तो भी उनका कुल जमा धन आर्कोलैब में उनके 42.5 लाख रुपए के निवेश से कहीं कम ही ठहरता है. उनकी आमदनी का कोई और जरिया भी था तो उन्होंने चार दिन तक चली पूछताछ के दौरान इस बारे में निदेशालय को कुछ नहीं बताया. कारण साफ है कि किसी ने उनसे इस बारे में पूछा ही नहीं.

बहरहाल, अजिताभ बच्चन को कई बातों का खुलासा तो करना ही चाहिए पर वे बातचीत के लिए मिले नहीं, न उनके भाई अमिताभ बच्चन ही मिले. मगर इतना साफ है, कि सरकार ने उन्हें भले ही पाक करार दे दिया हो, उनके मामले पर कई संदेह बरकरार हैं.

—पंकज पचौरी

बात पते की: कलमची

बिल पर बतरस

बोफोर्स और अजिताभ बच्चन के स्विस खातों की बाबत लोग अभी भूले भी न थे कि ललित सूरियों और सतीश शर्माओं के किस्से बच्चे-बच्चे की जुबान पर चढ़ गए. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. अब हमारे सामने मानहानि विधेयक और सैयद मोदी हत्याकांड जैसे घोटाले भी उछलने लगे हैं. पर गांव के झोंपड़ों में ठुसे पड़े जन-साधारण को इन सबसे क्या मतलब?

उत्तर प्रदेश के उपेक्षित पड़े 'खाया नहीं कही नहीं' गांव में कुछ बड़े-बूढ़े एक हुक्के के गिर्द जुटकर ऐसे मुद्दों की चर्चा में व्यस्त हैं जो शहरी बाबुओं का सिरदर्द बन गए हैं. उनकी बातचीत के कुछ अंश:

पहला ग्रामीण: आजकल इस मलहानि बिल की चर्चा बहुत सुनने में आ रही है. बड़ा गंभीर मामला है भाई. हमारी जिंदगी पर भी इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा. हमारे यहां पाखाने तो हैं नहीं, घर बनाने और जलावन के लिए हमें इसकी जरूरत है. हमें इतनी आजादी तो हो कि हम दिशा-मैदान.....

गांव का अध्यापक: अनपढ़ लाल, तुम नहीं समझे. मल-त्याग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. यह सब प्रेस वालों की उड़ाई हुई है.

दूसरा ग्रामीण: प्रेस वाले? मैं गांव का धोबी हूं, तो क्या यह मेरे लिए है?

तीसरा ग्रामीण: मैंने सुना है कि यह परिवार नियोजन जैसी ही एक चाल है. सरकार की कोशिश है कि हमारे....

ग्राम प्रधान: मैंने पंचायत वाले टीवी पर राजीव गांधी को देखा था. बोल रहे थे हम ऐसा कुछ नहीं...

गांव का मसखरा: वह राजीव गांधी था? मैंने सोचा हम जो फिल्म देख रहे थे वह उसका हीरो है. उसके डायलॉग तो एकदम फिल्मी थे और फिर रंगीन टीवी पर...

ग्राम प्रधान: उन्होंने कहा कि इसका मकसद गरीब लोगों की हिफाजत करना ही है.

तीसरा ग्रामीण: देखा! मैंने कहा था न कि इसका ताल्लुक परिवार नियोजन से है.

गांव का अध्यापक (धैर्य से): इसका संबंध विपक्ष और अखबार वालों से है जो हल और बैल की तरह जुते हुए हैं. बैल, मेरा मतलब है बिल का मकसद उन्हें लोगों पर धोखेबाजी का सीधा आरोप लगाने से रोकना है...

चौथा ग्रामीण: यानी कि संजय सिंह पर?

तीसरा ग्रामीण: यानी इसका ताल्लुक परिवार नियोजन से...

ग्राम प्रधान: अरे मूर्ख! वह दूसरा संजय था.

गांव का मसखरा: एक जैसे दो कैसे...

गांव का अध्यापक: चुप रह, मुझे बताने दे. अगर कोई किसी ईमानदार आदमी पर धोखेबाजी का आरोप लगाता है तो उसके पास इसका पक्का सबूत होना चाहिए. दस्तावेज काफी नहीं.

कार्टून अजीत नैनन

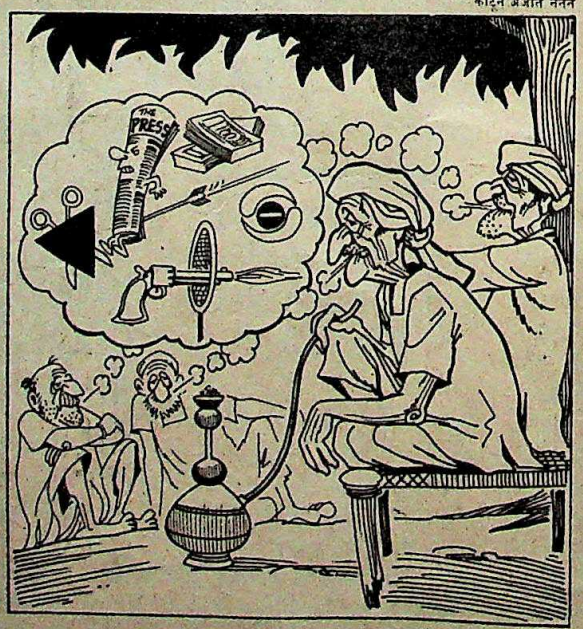

पहला ग्रामीण: मैं समझता था दस्तावेज और कागजात ही सबूत हैं. संजय सिंह के साथ प्रेम के मामले में अमिता मोदी की डायरी को ही लो. सीबीआई कहती है कि यह सबूत है.

गांव का अध्यापक: संजय सिंह विपक्ष में है. यह तो हुक्मरान पार्टी के लोगों के लिए है जिन पर दुष्कर्मों के आरोप लगाए जा रहे हैं.

दूसरा ग्रामीण: सबूत किस किस्म के चाहिए?

ग्राम प्रधान: उन्हें दूरदर्शन पर दुष्कर्म करते दिखाया जाए, तभी उनके खिलाफ सबूत माना जाएगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विजयपत सिंघानिया

जोखिम भरी उड़ान

साहसी उद्योगपति ने नया कीर्तिमान बनाया

नहीं, माइक्रोलाइट रेमंड्स के सूट के किसी नए कपड़े का नाम नहीं है. दरअसल यह ताबूत के आकार का फूहड़-सा दिखने वाला एक छोटा विमान है जिसमें रेमंड वूलन मिल्स के अरबपति अध्यक्ष 49 वर्षीय विजयपत सिंघानिया ने उड़ान भरकर रफ्तार का नया अंतरराष्ट्रीय रिकार्ड बनाया है. उन्होंने लंदन के पास बिग्गिन हिल से नई दिल्ली की 6000 मील की दूरी महज 23 दिन में तय की. इस तरह वे फेडरेशन एविएशन इंटरनेशनल (एफएआई) से मान्यताप्राप्त उड़ान रिकार्ड को तोड़ने वाले पहले भारतीय बन गए. उम्मीद है, एफएआई उनकी इस उपलब्धि पर अपनी मुहर लगा देगा.

थके-मांदे सिंघानिया जब 10 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर अपने विमान के तंग कॉकपिट से बाहर निकले तो उनका बहादुर की तरह स्वागत किया गया और इंग्लैंड के पत्रकार ब्रायन मिल्टन ने अपना 34 दिन का रिकार्ड तोड़ने के लिए उन्हें बधाई दी. प्रधानमंत्री कार्यालय में गृह राज्यमंत्री शीला दीक्षित ने सरकार की तरफ से उनका स्वागत करते हुए उनके इस साहसिक कार्य की तारीफ की. उन्होंने कहा, "हम जमीन पर रहते देश के लिए जितना करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप लोग हवा में उड़ते हुए करते हैं."

सिंघानिया का कहना था, "मैं अब एक हफ्ते सोऊंगा." अग्निपरीक्षा खत्म हो जाने के बाद बहादुर बनना आसान है. लेकिन सिंघानिया ने माना कि रास्ते में कई जगहों पर वे थोड़ा-बहुत भयभीत हो गए थे. भूमध्य सागर के ऊपर छह घंटे की लंबी उड़ान सबसे ज्यादा भयावह रही. सिंघानिया पूरी उड़ान के दौरान जीवन रक्षक जैकेट पहने हुए थे ताकि सागर में गिरने पर शार्क मछलियों का शिकार न बनें. जैकेट में इलेक्ट्रॉनिक संकट संकेतक यंत्र लगा था. और उनके घुटनों पर शार्क मछलियों को दूर रखने वाले पदार्थ से भरा एक डिब्बा बंधा था. बोरियत दूर करने के लिए वे अपनी दो साल की पोती अनन्या से काल्पनिक बातचीत करने लगते. उसका चित्र उन्होंने कॉकपिट में अपने पारिवारिक देवी-देवताओं के साथ लगा रखा था.

यदि उनकी पोती की तस्वीर ने आसमान में उनका साथ दिया तो उनकी पत्नी आशा ने कम-से-कम अम्मान (जॉर्डन) से अरार (सऊदी अरब) तक जमीन पर मीलों उनका साथ दिया. सऊदी सीमा शुल्क और आप्रवासन अधिकारियों ने उन्हें पांच घंटे तक रोके रखा जबकि उनके पति अरार हवाई अड्डे पर उनका इंतजार कर रहे थे. आखिरकार जब वे वहां पहुंचीं तो सिंघानिया ने उन्हें किसी एअरलाइंस के विमान से जाने की सलाह दी क्योंकि वे उड़ान के तनाव के साथ-साथ पत्नी के द्वारा बिना वातानुकूलित कार में रेगिस्तान का सफर करने का तनाव झेलने की स्थिति में नहीं थे. पत्नी भी उनके बारे में चिंतित थी. ग्वादर (पाकिस्तान) से उड़ान भरने के बाद जब उनका विमान भुज में भारतीय जमीन पर उतरा तो उनकी अगवानी करने वालों में आशा सिंघानिया नहीं थीं. वे कानपुर के द्वारकाधीश मंदिर में भगवान को धन्यवाद दे रही थीं. सफदरजंग हवाई अड्डे पर अपने पति की अगवानी करते उन्होंने कहा कि "वे ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं."

अब उनके माइक्रोलाइट विमान का क्या होगा? सिंघानिया ने कहा कि वे उसे अपने पास रखना ही पसंद करेंगे. लेकिन यदि सरकार 3.4 लाख रु. की कीमत वाले इस विमान को किसी संग्रहालय में रखना चाहेगी तो वे इसे दान करने की सोचेंगे. सीमा शुल्क विभाग के कुछ अधिकारी हवाई अड्डे पर 'ल एस्प्री द इंडियन पोस्ट' विमान को अपने कब्जे में लेने के लिए मौजूद थे.

मोटे तौर पर एक माइक्रोलाइट का वजन 150 किग्रा से कम होता है और उसके पंखों का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग-मीटर होता है. सिंघानिया ने जिस माइक्रोलाइट से उड़ान भरी वह 150 किग्रा से थोड़ा भारी है और उसका इंजन एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल से थोड़ी ही अधिक अश्वशक्ति पैदा करता है. इसका हरेक प्रोपेलर ब्लेड तकरीबन दो फुट लंबा है और इसके छोटे इंजन से किसी विमान की बजाय राजदूत यामाहा मोटरसाइकिल जैसी आवाज निकलती है. सिंघानिया कहते हैं, "इससे पत्नी के बजाय प्रेमिका जैसा बर्ताव करें तो यह अच्छा काम अंजाम देता है."

क्या वे इससे फिर कभी उड़ान भरेंगे? "इस तरह का साहस भरा कार्य जिंदगी में एक बार के लिए काफी होता है." कई लोगों को इस बात पर ताज्जुब होता है कि एक बड़े उद्योगपति ने तुच्छ दिखने वाले माइक्रोलाइट विमान से दो महाद्वीपों को पार करने का खतरा क्यों मोल लिया? सिंघानिया का जवाब था, "मेरे पास अपने पोते-पोतियों को सुनाने के लिए किस्से-कहानियां नहीं बची थीं." और फिर यह कौन जानता है कि रेमंड्स इस उपलब्धि को भुनाए और माइक्रोलाइट समर सूटिंग्स का एक नया रेंज निकाल दे. —रमिंदर सिंह

प्रशांत पंजियार

पुराने रिकार्डधारी मिल्टन (बाएं) दिल्ली में सिंघानिया को बधाई देते हुए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आंध्र प्रदेश

बाजी उलटने से बड़ा फायदा

रामराव इंका आंदोलन की हवा सरकाने में कामयाब

परदे पर तो उनका कोई जोड़ नहीं था. पर इस बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव ने परदे के पीछे रहकर ही कमाल दिखा दिया. राज्य इंका का आंदोलन बेकाबू होने ही लगा था कि उन्होंने लड़ाई का मैदान दिल्ली लाकर बाजी पलट दी. विशेष संवाददाता ***अमरनाथ के. मेनन*** *की रिपोर्ट:*

पहला दृश्य: हैदराबाद: आंध्र प्रदेश विधानसभा में सदन के बीचोबीच भूख हड़ताल पर बैठे इंका विधायकों को जबरदस्ती उठाकर बाहर कर दिया जाता है. वे सूखा क्षेत्र रायलसीमा में सिंचाई के लिए अधिक पानी न दिए जाने का विरोध कर रहे हैं.

दूसरा दृश्य: नई दिल्ली: तेलुगु देशम विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के झुंड के झुंड पीले वस्त्र पहने बोट क्लब के मैदान में आ जुटे हैं. वे केंद्र सरकार द्वारा राज्य की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की मंजूरी न देने का विरोध कर रहे हैं. प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसकी अनदेखी कर जाते हैं.

तीसरा दृश्य: प्रधानमंत्री का निवास: तेलुगु देशम विधायकों के एक जुलूस द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़े जाने पर पुलिस लाठीचार्ज करती है. भगदड़ में नौ विधायक घायल होते हैं और 163 लोग गिरफ्तार.

आखिरी दृश्य: इस घटना के विरोध में विपक्षी दल मानसून सत्र के बाकी तीन दिन संसद का बहिष्कार करते हैं. आंदोलनकारी विधायकों के भारी स्वागत के लिए मुख्यमंत्री रामराव हैदराबाद हवाई अड्डे पर आते हैं. इसके बाद राज्यव्यापी सफल बंद.

मुख्यमंत्री रामराव ने राज्य में इंका आंदोलन की हवा सरकाकर उसके नेताओं के पैरों तले की जमीन हिला दी. उधर, राजीव गांधी ने उनको केंद्र पर 'राज्य की छह करोड़ तेलुगुभाषी जनता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने' का आरोप लगाने का मौका फिर मुहैया करा दिया. राज्य के स्वास्थ्य-मंत्री डॉ. डी. वेंकटेश्वर राव कहते हैं, "मैंने सोचा भी नहीं था कि राजीव गांधी इतने मूर्ख हैं. उन्होंने अपनी इस कार्रवाई से तेलुगु देशम की मदद ही की है."

इंका ने इस नुकसान को कमतर करने की जी-तोड़ कोशिश की. केंद्रीय उद्योगमंत्री और आंध्र प्रदेश इंका अध्यक्ष जे. वेंगलराव तथा केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री पी. शिवशंकर ने इस पूरे प्रकरण को रामराव की नाटकीय प्रतिभा की एक और मिसाल करार दिया. लेकिन हैदराबाद में इंका के एक परेशान नेता ने माना, "इससे राज्य में सत्ता में लौटने की हमारी संभावनाओं पर पानी फिर गया है."

इस उलझन भरी स्थिति की जिम्मेदार खुद इंका ही है. रामराव को मुश्किल में डालने और राज्य में अपनी घटती लोकप्रियता को बचाने के लिए पार्टी ने रायलसीमा क्षेत्र की समस्याओं को उछालने का फैसला किया था.

प्रमोद पुष्करणा

"इंका की धैर्य परीक्षा ज्यादा देर नहीं चल सकती. अगर हमने आंदोलन शुरू कर दिया तो वह रामराव सरकार के गिरने तक रुकेगा नहीं"

जे. वेंगलराव

प्रधानमंत्री निवास के पास आंध्र के विधायकों पर आंसू गैस: राज्य की लड़ाई दिल्ली में

CC-0. In Public Domain. Gur... ...war

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुरनूल, कड्डपा, अनंतपुर और चित्तूर के दक्षिणी जिलों से मिलकर बना रायलसीमा क्षेत्र राज्य का सूखे की सबसे ज्यादा आशंका वाला इलाका है. इस क्षेत्र की अनुमानित 30 लाख हेक्टेयर कृषियोग्य भूमि को सिंचाई के लिए फिलहाल कृष्णा और तुंगभद्रा बांध परियोजनाओ से महज 235 अरब घनफुट पानी ही मिलता है. इलाके के इंका विधायकों के मुताबिक यहां की दो-तिहाई कृषियोग्य भूमि की सिंचाई के लिए 370 अरब घनफुट अतिरिक्त पानी चाहिए.

18 अगस्त को उन्होंने विधानसभा में भूख हड़ताल शुरू कर दी. उनकी मांग थी कि तेलुगु गंगा परियोजना से इस इलाके के लिए पानी दिया जाए. इसके अलावा वे 13 प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं की समय सीमा भी तय कराना चाहते थे. रामराव के इस आश्वासन के बावजूद कि इलाके में सिंचाई जल के आबंटन पर पुनर्विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी, उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा. सभी सत्तारूढ़ तेलुगु देशम ने भी आक्रामक रुख अख्तियार करने का फैसला किया.

बताया गया है कि पिछले पांच साल में राज्य सरकार बड़ी, मझोली और छोटी परियोजनाओं पर 296 करोड़ रु. से अधिक खर्च कर चुकी है और अगले मार्च तक 68 करोड़ रु. और खर्च करने की योजना है. रायलसीमा क्षेत्र के निवासी और इंका सरकार में मंत्री रह चुके राज्य के सिंचाईमंत्री के.ई. कृष्णामूर्ति कहते हैं, "इंका सरकार ने 34 साल में रायलसीमा की सिंचाई के लिए जितना पैसा लगाया उससे कहीं अधिक हमने पांच साल में खर्च किया है."

आंदोलनकारी विधायकों को एक चिट्ठी में रामराव ने इस ओर इशारा किया कि क्षेत्र की सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए बनाई गई 843 करोड़ रु. की तेलुगु गंगा परियोजना में केंद्र सरकार ने ही अड़ंगा लगा रखा है. रामराव ने लिखा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल में आंध्र के तीन नेता हैं. फिर भी राज्य के प्रति केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया साफ झलकता है." इस पर भी आंदोलनकारी इंका विधायक अड़े रहे तो रामराव ने लड़ाई का रुख दिल्ली की ओर किया.

इस बार उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए पूरी कसरत कर रखी थी. तेलुगु देशम ने 32 पृष्ठों की एक पुस्तिका निकाली जिसमें लटकी चली आ रही परियोजनाओं और प्रस्तावों की ढेर सारी फाइलों का जिक्र है. 'अति आवश्यक' का निशान लगाकर भारत सरकार के पास भेजी गई ये फाइलें लालफीते में बंद हैं. पुस्तिका में 22 सिंचाई परियोजनाओं और हैदराबाद से सिकंदराबाद के बीच सर्कुलर रेल बनाने जैसे 15 दूसरे प्रस्तावों की सूची भी दी गई है जिन्हें अभी केंद्र से मंजूरी मिलना बाकी है. इन परियोजनाओं पर करीब 10,000 करोड़ रु. खर्च बैठता है. इसलिए केंद्र सरकार के लिए इन्हें मंजूरी देना नामुमकिन है. लेकिन जांच से पता चलता है कि केंद्र ने कई परियोजनाओं को तो किसी जायज कारण के बिना ही लटका रखा है. मसलन 1990 में पूरी होने वाली तेलुगु गंगा के लिए केंद्र ने अभी तक 210 करोड़ रु. ही दिए हैं.

प्रशांत पंजियार

प्रशांत पंजियार

"केंद्रीय मंत्रिमंडल में आंध्र प्रदेश के तीन नेता हैं. फिर भी राज्य के प्रति केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया साफ तौर पर झलकता है"

नंदमूरि तारक रामराव

राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग से ही नहीं जूझना पड़ा. तेलुगु गंगा परियोजना के तहत 25,000 एकड़ संरक्षित वनभूमि भी आने वाली है. राज्य सरकार इसके लिए 35,000 एकड़ यानी जरूरत से 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन मुहैया करवा रही है. इसके अलावा नए जंगल लगाने के लिए भी वह 24 करोड़ रु. देने जा रही है. लेकिन मामला वन संरक्षण कानून के तहत लटका पड़ा है क्योंकि इससे विस्थापित होने वाले लोगों की पुनर्वास समस्या भी जुड़ी हुई है. हालांकि राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए विस्तृत योजना पेश कर दी है.

एक दूसरा मामला 1983 से लटका पड़ा है. आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एपीई-डीसी) के अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश की ऐसी इकाइयों को पांच-पांच लाख टीवी पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन करने के आशयपत्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिए गए. पंजाब इकाई को हिताची और उत्तर प्रदेश इकाई को तोशिबा से सहयोग मिलना तय हुआ जबकि एपीईडीसी को फिलिप्स से सहयोग लेना था. बाकी दोनों परियोजनाओं को तो मंजूरी दे दी गई लेकिन एपीईडीसी का प्रस्ताव अभी भी धूल चाट रहा है.

केंद्र सरकार ने सात पेजी एक चिट्ठी में इन आरोपों का खंडन किया. उसका कहना है कि पिछले पांच साल में बिजली की सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि सिंचाई परियोजनाओं में देरी का कारण राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल है. आंध्र प्रदेश के मामले में ही छठी योजना के अंत तक विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं में 4,111 करोड़ रु. से अधिक रकम लगी पड़ी है.

आरोपों-प्रत्यारोपों के मद्देनजर अभी इस नाटक का अंत होता नहीं दिखता. दोनों ही तरफ से अब करो या मरो की लड़ाई की शेखियां बघारी जा रही हैं. इंका विधायक अभी भी रायलसीमा के मुद्दे पर अड़े हुए हैं. 19 सितंबर से उन्होंने सभी चार जिलों में जनसभाएं आयोजित करने की योजना बनाई है. इसके अंतिम चरण में वे 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के दिन भूख हड़ताल करेंगे. इंका के पूर्व मंत्री डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी कहते हैं, "यह लड़ाई कई चरणों में लड़ी जाएगी." उनकी मांग यह भी है कि स्वायत्तशासी रायलसीमा विकास परिषद बनाने के लिए संसद में कानून पास किया जाए.

इसके जवाब में तेलुगु देशम समेत दूसरी पार्टियां भी 22 सितंबर से महीने भर के आंदोलन के दौरान रैलियां आयोजित करेंगी. वे आंध्र प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं को अनुदान और मंजूरी देने में देरी के लिए केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट करेंगी.

जाहिर है, तेलुगु देशम को परेशान करने की इंकाई कोशिशों का असर उलटा पड़ने लगा है. यह अशुभ संकेत भी है कि केंद्र-राज्य के बीच संबंध बदतर होंगे और लड़ाई खुलकर सड़क पर आ जाएगी. वेंगलराव चेतावनी देते हैं, "इंका की धैर्य परीक्षा ज्यादा देर नहीं चल सकती. अगर हमने आंदोलन शुरू कर दिया तो वह रामराव सरकार के गिरने तक रुकेगा नहीं. हम महापौरों और नगरपालिका अध्यक्षों को मुख्यमंत्री के घर पर जाकर अनुदान राशि की मंजूरी तक धरना देने के लिए तैयार कर सकते हैं."

भवान सिंह

तेलुगु देशम की मांगों के समर्थन में विपक्षी नेताओं की बैठक

नगेंद्र राव

आंध्र प्रदेश विधानसभा में विरोध जता रहे इंका विधायकों का सदन-निकाला

यह धमकी मामूली नहीं है. इसके अलावा तथ्य तो यह है कि आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं की मंजूरी के मामले में आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप पूरी तरह सही नहीं है. तेलुगु देशम के पांच साल से अधिक के शासन के दौरान कई बिजली परियोजनाओं को मंजूरी मिली है.

अनेक राज्यों में यह आम प्रचलन है कि पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रकम न होने पर भी नई योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है. तेलुगु देशम के लिए यह सफाई देना मुश्किल होगा कि पार्टी के 1982 के पहले चुनाव घोषणापत्र में मंगलागिरि टायर कारखाना परियोजना के बारे में किए गए वायदे का क्या हुआ और योजना आयोग द्वारा मंजूर कई दूसरी परियोजनाओं पर काम शुरू करवाने में क्या दिक्कत थी.

जैसा कि राज्य के योजनाकार बताते हैं कि सबसे पहली जरूरत तो प्राथमिकताएं तय करने की है. इस तरह, अगर एक परियोजना की मंजूरी में देरी की आशा हो तो रकम दूसरी पर खर्च की जा सकती है.

लेकिन राज्य में फिलहाल जिस तरह का राजनैतिक खेल चल रहा है उसके मद्देनजर सिंचाई के मुद्दे से शुरू हुई यह बजट की लड़ाई ऐसी स्थिति में पहुंच सकती है जहां पानी से अधिक खून ही बहने की उम्मीद है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दुनियादारी की समझ

मध्य प्रदेश के पत्रकारों को इस बार अर्जुन सिंह का नया ही रूप दिख रहा है. कुछ अखबार तो ऐसे हैं, जिनके लिए उनके पास कभी वक्त नहीं होता. 1980-85 के अपने पहले कार्यकाल में किसी दो-पेजी अखबार का मालिक भी पहले से वक्त लिए बिना जब चाहे उनसे मिल सकता था. इस उदार रवैये के कारण ही उस दौरान मध्य प्रदेश के छोटे साप्ताहिकों की चांदी रही.

अर्जुन सिंह

लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. छोटे-मोटे साप्ताहिकों और कभी-कभार दर्शन देते दैनिकों के संपादकों के अलावा पत्रकारों के लबादे में दलालों का मुख्यमंत्री निवास पर पहले-सी गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया जाता. इस रवैये से दुखी एक पत्रकार का कहना है, "हम मुख्यमंत्री सचिवालय में मुलाकात के लिए रोज फोन करते हैं. पर महीनों तक कोई जवाब ही नहीं मिलता." निराश पत्रकारों ने हाल ही में एकजुट होकर मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया. लेकिन राष्ट्रीय दैनिकों और प्रमुख स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं के संवाददाताओं को अर्जुन सिंह से मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं. पंजाब में राज्यपाल और केंद्र में मंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री में दुनियादारी की समझ शायद ज्यादा हो गई है.

क्लब में कटुतापूर्ण कलह

मौका तो खुशियां मनाने का था पर कलकत्ता के मोहन बागान क्लब के सदस्यों की आपसी कलह और गुटबंदी के कारण पिछले पखवाड़े उसके शताब्दी समारोहों के रंग में भंग पड़ गया. अंदरूनी लड़ाई के चलते क्लब की गतिविधियां भी ठप पड़ गई हैं. कुछ सदस्यों ने तो केंद्रीय खेल राज्यमंत्री मारग्रेट अल्वा को एक चिट्ठी में क्लब को 'राष्ट्रीय संस्थान' का दर्जा न देने का भी अनुरोध किया है. उद्घोषक सुरजीत देब कहते हैं, "भारतीय फुटबाल में मोहन बागान जैसे अग्रणी क्लब को यह शोभा नहीं देता."

सैबल दास

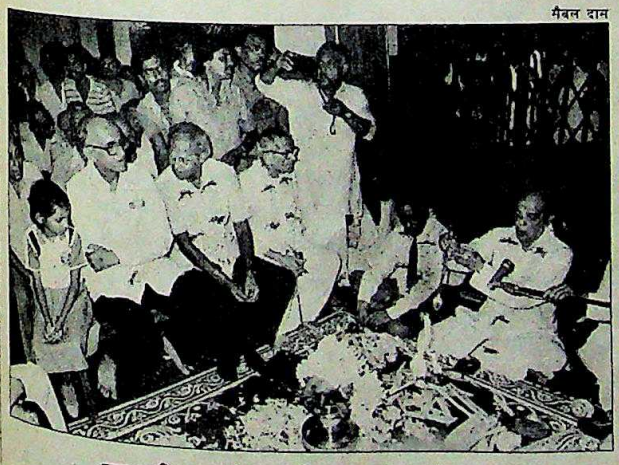

शताब्दी समारोह पर यज्ञ का आयोजन

मोहन बागान के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी कहते हैं, "क्लब को वे ही लोग बदनाम कर रहे हैं, जो इस शताब्दी वर्ष में प्रचार पाने के लिए आगे आना चाहते हैं." बताया जाता है कि सारा विवाद क्लब के सचिव, 80 वर्षीय धीरेन दे और उनकी मित्रमंडली पर केंद्रित है. उन पर सभी कायदे-कानूनों को ताक पर रखने और क्लब का पैसा गबन करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं.

कई सदस्यों का मानना है कि क्लब के ज्यादातर पदाधिकारी बहुत बूढ़े हो चुके हैं. उनकी जगह युवा लोगों को लाना बहुत जरूरी है जिससे क्लब की गतिविधियों में नई जान फूंकी जा सके. लेकिन लड़ाई थमने के आसार नजर नहीं आ रहे जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है. अब हालत तो यह है कि क्लब को पुराना सम्मान दिलाना ब्राजील की फुटबाल टीम को हराने से भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है.

मुख्यमंत्री की मुश्कें कसीं

ओडीसा के मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक अपनी कट्टर विरोधी नंदिनी सतपथी की इंका में वापसी के सदमे से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि केंद्र ने उन पर एक और प्रहार कर दिया. प्रदेश इंका समिति के पुनर्गठन में उनके किसी समर्थक को लेना तो दूर, गंगाधर महापात्र और हेमनंद बिस्वाल जैसे असंतुष्टों को क्रमशः सहअध्यक्ष और प्रथम महासचिव नियुक्त कर दिया गया. हैरानी की बात तो यह है कि समिति के ज्यादातर सदस्य विधायक भी नहीं हैं.

प्रमोद पुष्करणा

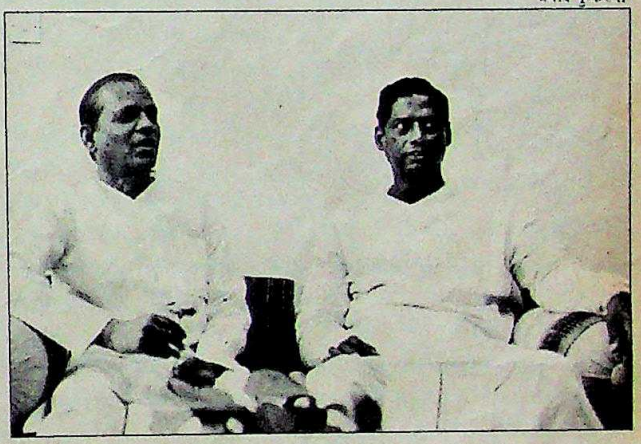

पटनायक (बाएं) और लेंका: नए समीकरण

इस बार समिति में हरिजनों और वनवासियों को ज्यादा जगहें दी गई हैं. असंतुष्ट अरसे से शिकायत कर रहे थे कि 'पटनायक राज' में इन लोगों की घोर उपेक्षा हुई है जिससे पार्टी के इस 'वोट बैंक' के खिसक जाने का खतरा पैदा हो गया है.

पुनर्गठन की इस कसरत में सबसे ज्यादा फायदे में रहे प्रदेश इंका अध्यक्ष और सांसद कालीचरण लेंका. नई समिति में उनके समर्थकों की भरमार तो है ही, उनके विरोधी बसंत कुमार बिस्वाल को भी कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है. हालांकि बिस्वाल को हटाना पटनायक के लिए तसल्ली की बात हो सकती है क्योंकि 1981 में मंत्रिमंडल से निकाले जाने के बाद वे मुखर असंतुष्ट बने हुए थे लेकिन कुल मिलाकर पासा लेंका के ही पक्ष में रहा. प्रेक्षकों का कहना है प्रदेश इंका का यह पुनर्गठन चुनावों को ध्यान में रखकर ही किया गया है और केंद्र लेंका को राज्य के शक्तिशाली नेता के रूप में उभारने की कोशिश कर रहा है. एक असंतुष्ट नेता चहकते हुए कहते हैं, "इस बार पटनायक की कुर्सी भले ही बच गई हो पर आलाकमान की नजरों में उनका महत्व निश्चय ही घटा है." उधर, पटनायक समर्थकों का कहना है कि केंद्र ने यह कदम आगामी चुनाव के मद्देनजर असंतुष्टों को खुश करने के लिए उठाया है. आलाकमान के मूड को भांपना वाकई आसान नहीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भ्रष्टाचार रोकने की मुहिम

भ्रष्टाचार रोकने की एक और मुहिम इन दिनों जोरों पर हैं. राष्ट्रपति शासन वाले तमिलनाडु में राज्यपाल के सलाहकार जी.वी. रामकृष्ण ने अचानक ही सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को हरकत में ला दिया है. विभाग राज्य के 15 आईएएस अधिकारियों के आचरण की कड़ी जांच कर रहा है.

रामकृष्ण

इसके घेरे में वे लोग भी आ गए हैं जो भूमि विकास नियमों का उल्लंघन करते आ रहे हैं. रामकृष्ण ने वैज्ञानिकों और सिविल इंजीनियरों से इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर हुए अनधिकृत निर्माण को गिराने के तरीके सुझाने को कहा है. इस बीच, कई मामलों में मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण के निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए भी अर्जियां मिल रही हैं.

मगर नए अभियान से एक नए किस्म का भ्रष्टाचार पनपा है. दिवंगत एमजीआर के जमाने में फाइलों को तेजी से सरकाने के लिए रिश्वत दी जाती थी, अब धीमे सरकाने के लिए. रामकृष्ण भी मानते हैं, "मुझे खबर मिली है कि अब फाइलें 'धीमे खिसकाने' के लिए रिश्वत दी जा रही है." नौकरशाही की महिमा अपरंपार है!

दामाद हैं तो क्या हुआ

हाईकोर्ट की कटु टिप्पणियां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रामराव का पीछा छोड़ती नहीं लगतीं. इस बार अदालत ने 31 अगस्त को दिए फैसले में उनके दामाद एन. चंद्रबाबू नायडू को राष्ट्रीय कृषक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के मामले में रामराव की आलोचना की है. न्यायमूर्ति वी.पी. जीवन रेड्डी और वाई. भास्कर राव ने नायडू की नियुक्ति को रद्द करते हुए टिप्पणी की, "यह या तो पूरी तरह मनमानापन और सनक में की गई कार्रवाई है या फिर उपयुक्त अधिकारी (कृषि निदेशक) का अपने राजनैतिक आकाओं के दबाव में आ जाने का नतीजा है."

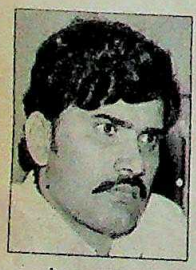
चंद्रबाबू नायडू

फैसले की भनक पाकर ही शायद तेलुगु देशम ने तत्काल इस कानून के बारे में एक संशोधन विधेयक पेश कर दिया. लेकिन 114 पृष्ठों के इस प्रतिकूल फैसले के बाद परिषद और राज्य सरकार को न्यायाधीशों से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति लेनी पड़ी.

1984 में पार्टी महासचिव नियुक्त हुए नायडू पिछले साल उस समय संकट में पड़ गए जब इंका ने तेलुगु देशम के एक विधायक की चिट्ठी पेश की जिसमें नायडू पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था. रामराव ने इस पर जांच बिठाई भी पर अभी इसने काम शुरू नहीं किया है. बाद में उन्होंने अपने दामाद को किसानों के बीच आधार बनाने को कहा. वे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, "सामुदायिक मंडी और चीनी कारखाने बनाकर हमने तो शुरुआत भर की है. परिषद का मकसद पूरी तरह तभी समझ में आएगा जब मध्य '89 तक इसके नतीजे दिखने लगेंगे." शायद इसी वजह से दूसरी राजनैतिक पार्टियां, खासकर माकपा, अब राज्यपाल कुमुदबेन जोशी से इस संशोधित कानून को मंजूरी न देने का अनुरोध कर रही हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक कानून का राज खत्म करने का ही एक प्रयास है.

उन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा

कोई मिसाल कायम करना ताकि दूसरे उस पर चल सकें, दरअसल यह हमारे नेताओं की परंपरा नहीं है. लेकिन कानपुर के एक जन स्वास्थ्य केंद्र के रिकार्ड को अगर सही माना जाए तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी ही सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी करा ली है.

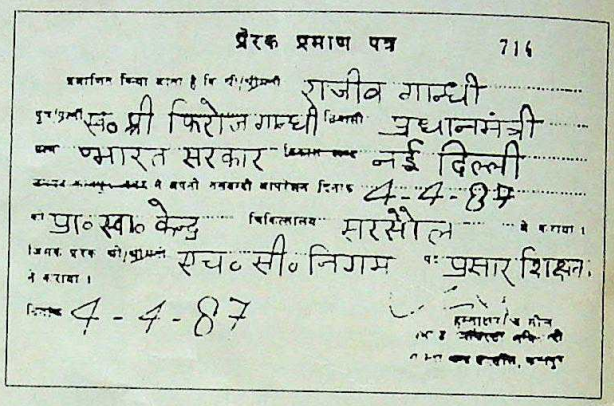
प्रेरक प्रमाण पत्र 716

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती राजीव गान्धी
पुत्र/पुत्री स० श्री फिरोज गान्धी निवासी प्रधानमंत्री
ग्राम भारत सरकार विकास खण्ड नई दिल्ली
जनपद कानपुर ने अपनी नसबन्दी आपरेशन दिनांक 4-4-87
को प्रा० स्वा० केन्द्र चिकित्सालय सरसौल में कराया।
जिसके प्रेरक श्री/श्रीमती एच० सी० निगम पद प्रसार शिक्षक
ने कराया।
दिनांक 4-4-87

नसबंदी का प्रमाणपत्र: अटकलबाजियां

इसका सबूत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ ने जारी किया है. एक सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी के अनुसार प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 4 अप्रैल 1987 को कानपुर के एक गांव सिरसौल के स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था.

संघ के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अगर सचमुच नसबंदी नहीं कराई है तो जाहिर है स्वास्थ्य केंद्र में कोटा पूरा करने के लिए नसबंदी के फर्जी आंकडे दर्ज किए जाते हैं.

लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछने पर बताया कि मामले की जांच की जा रही है. बहरहाल, अटकलों का बाजार तो गर्म हो ही गया है.

बर्र के छत्ते छेड़ने की आदत

परेशानी मोल लेना हिमाचल प्रदेश के विधायक और राज्य जनमोर्चा के संयोजक विजय सिंह मनकोटिया का शगल बन गया लगता है. वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ मुहिम चला रहे इस विद्रोही विधायक को पिछले पखवाड़े फिर संकट का सामना करना पड़ा. उनके एक बयान पर विशेषाधिकार समिति ने उन्हें एक हफ्ते बचे सत्र तक के लिए सदन से मुअत्तल कर दिया.

मामला करीब एक साल पहले शुरू हुआ जब मनकोटिया ने एक प्रेस बयान में सरकार पर आरोप लगाया कि वह उनके कुछ खोजपरक सवालों को सदन में नहीं उठने दे रही. उनकी यह हरकत आचार संहिता का सरासर उल्लंघन मानी गई. इसके तहत कोई भी विधायक सदन में लंबित कार्रवाई को विधानसभा से बाहर जाहिर नहीं कर सकता.

मनकोटिया पर राज्य के परिवहनमंत्री सत महाजन ने भी मानहानि के आठ मामले दायर करा रखे हैं. दो और विशेषाधिकार प्रस्ताव उनके खिलाफ लाए जाने वाले हैं. पर अविचलित मनकोटिया ने चालू सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से रोजाना पांच सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया. सदन में इन सवालों को ही उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी. उनकी मुअत्तली ने खेल भले ही बिगाड़ दिया हो पर उनका कहना है, "मुझे इतनी आसानी से तो चुप नहीं कराया जा सकता."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न्यूयॉर्क

लापरवाही से होता घाटा

दूतावास की जमीन खाली

यह जगजाहिर है कि न्यूयॉर्क का मैनहटन इलाका बेहद महंगा है. यहां जायदाद हो तो क्या कहने. लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूतावास (पीएमआई) का नजरिया कुछ और ही है.

घनी आबादी वाले इस शहर में मौके की जगह—सेकंड एवेन्यू की 43वीं व 44वीं गली के बीच 6500 वर्गफुट जमीन की मिल्कियत पीएमआई के पास अगस्त '88 से है. लेकिन यह जमीन यों ही पड़ी है. जब इस इलाके में दफ्तर हो तो हर महीने प्रति वर्गफुट 4 डॉलर (57 रुपए) का किराया वसूला जा सकता है. और दुकान वगैरह का किराया 25,000 डॉलर (3.60 लाख रु.) प्रतिमाह तक वसूला जा सकता है. लेकिन यह भारतीय विदेश मंत्रालय की दूरदर्शिता और आर्थिक सूझबूझ का ही परिचायक है कि उसने दूतावास और इसके कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के इरादे से आठ साल पहले 10 लाख डॉलर (1.44 करोड़ रु.) की जमीन खरीद ली. बाजार में इसकी वर्तमान कीमत तकरीबन 30 लाख डॉलर (4.32 करोड़ रु.) है.

इन वर्षों में इस जमीन पर तो कचरा भरता गया है और पीएमआई अपना दफ्तर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रही. पहले दफ्तर के किराए पर 10 हजार डॉलर प्रति माह खर्च करने पड़ते थे, अब 36 हजार डॉलर (5.18 लाख रु.) खर्च करने पड़ रहे हैं. दफ्तर बदलने की प्रक्रियाओं में 50,000 डॉलर (7.20 लाख रु.) अलग से खर्च हुए. और तो और, दूतावास के अधिकारियों को आवास किराया भत्ता बढ़ाकर 3,500 डॉलर (50,400 रु.) प्रति माह करना पड़ा है.

1980 में पीएमआई ने अगर थोड़ी तत्परता दिखाई होती तो वह इस जमीन पर 19 मंजिली इमारत खड़ी करके एक लाख वर्गफुट रिहायशी क्षेत्र बना सकती थी. 1984 में कानूनों में की गई तब्दीली के कारण अब वहां केवल 13 मंजिली इमारत ही बनाई जा सकती है. और सबसे अहम बात तो यह कि जब तक जमीन खाली पड़ी रहती है और उस पर निर्माण की योजना नहीं पेश की जाती तब तक हर तिमाही 10,000 डॉलर (1.44 लाख रु.) संपत्ति कर के रूप में अदा करते रहना होगा. कूटनीतिक स्तर पर इस कर से छुटकारा पाने की कोशिश की गई लेकिन नगर प्रशासन ने अनुरोध ठुकरा दिया.

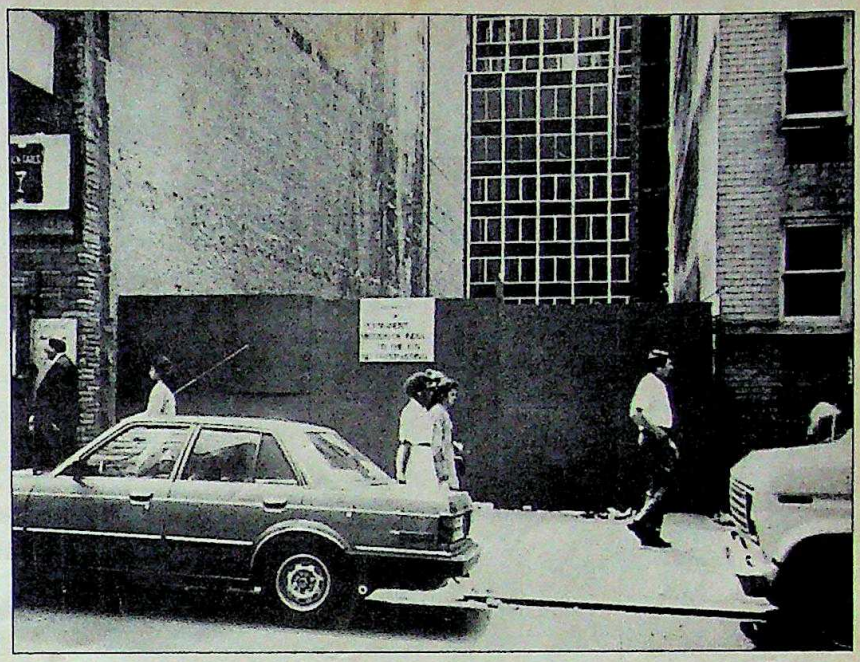

बेकार पड़ी बेशकीमती जमीन

इस्तेमाल की कोई योजना न होने से जमीन पर कचरा भर रहा है. सरकार को तिमाही 1.44 लाख रु. संपत्ति कर अलग भरना पड़ रहा है

दो साल तक बेवजह इंतजार करने के बाद 1982 में भारत सरकार ने 20 अमेरिकी और भारतीय वास्तुशिल्पियों से पीएमआई कार्यालय का डिजाइन तैयार करने और निर्माण लागत का अनुमान देने को कहा. चार लोगों के सुझाव पसंद किए गए. इनमें एक वास्तुशिल्पी भारतीय हैं जो अपने उच्चस्तरीय राजनैतिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं. कहा जाता है कि इससे भी फैसला प्रभावित हुआ.

प्रस्ताव में अड़ंगा एक और हलके की ओर से डाला गया. प्रस्तावित इमारत में वरिष्ठ के साथ-साथ कनिष्ठ कर्मचारियों के क्वार्टर भी बनने थे. वरिष्ठ अधिकारियों के गले यह बात नहीं उतरी. उन्होंने इस प्रस्ताव को दफनाने की ही जुगत लगा दी.

विदेश मंत्रालय ने 1984 में इस रुकी हुई योजना को पूरा करने की एक और गंभीर कोशिश की. उसने जाने-माने भारतीय वास्तुशिल्पी चार्ल्स कोरिआ को योजना तैयार करने का न्यौता दिया. बताया जाता है कि उनका प्रस्ताव मंत्रालय को भी पसंद आया. लेकिन वह भी उपेक्षित ही पड़ा हुआ है. पिछले साल तत्कालीन वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने महंगी साबित होती इस देरी पर असंतोष जाहिर किया और वादा किया कि वे इस योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलवा ही देंगे. लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल के कारण उनके नेक इरादों पर अमल न हो सका जबकि कोरिआ की योजना 25 लाख डॉलर से ज्यादा की नहीं है.

अब क्या कुछ किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सी.आर. गरेखां के मुताबिक, "अंतिम फैसले के लिए इस महीने के आखिर में विदेश मंत्रालय का एक विशेष दल न्यूयॉर्क आने वाला है." देरी की वजह पूछने पर गरेखां का कहना था कि वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए अभी दो महीने पहले ही तो धनराशि स्वीकृत की है. लेकिन वे यह भी कहते हैं, "विदेशों में सरकारी प्लॉट का वर्षों तक खाली पड़ा रहना कोई असामान्य बात नहीं है. आप तो जानते हैं कि इस किस्म की चीजें आम तौर पर चलती ही रहती हैं."

—अमृत ककरिया, न्यूयॉर्क में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस्राएल

नाजुक रिश्ते में नया मोड़

छह साल बाद भारत के साथ फिर से कूटनीतिक संबंध कायम

घोषणा तो छोटी-सी थी लेकिन इसके नतीजे खासे महत्वपूर्ण थे. तकरीबन छह साल बाद पिछले महीने भारत ने इस्राएल के साथ फिर से अपना कूटनीतिक संबंध जोड़ लिया. और उसे पुराना दर्जा प्रदान कर दिया—बंबई में वाणिज्यदूत के द्वारा प्रतिनिधित्व का. इस्राएल का कूटनीतिक दर्जा 1982 में घटा दिया गया था. तब उसके वाणिज्यदूत यूसुफ हासनी को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक अखबार के साथ अपनी बातचीत में भारतीय विदेश नीति की कड़ी आलोचना कर दी थी. अब नए फैसले के बारे में बंबई में तैनात इस्राएल के खूबसूरत और मितभाषी वाणिज्यदूत 36 वर्षीय आमोस रादियां कहते हैं, "यह सही दिशा में उठाया गया कदम है."

हालांकि पिछले छह वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को भारी नुकसान पहुंचा है लेकिन रादियां का कहना है कि सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचा. इस दौरान इस्राएल आने वाले भारतीयों की संख्या दोगुनी (हर महीने करीब 300) हो गई और व्यापार में भी इजाफा हुआ. रादियां कहते हैं, "इस्राएल भारत से हमेशा करीबी रिश्ता कायम करने की तमन्ना करता रहा है."

लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की भी ऐसी तमन्ना रही है? इस्राएल समान लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर रिश्तों की बुनियाद रखना चाहता रहा है. उसने तो कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय पक्ष का समर्थन तक किया. लेकिन भारत फिलस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकारों की हमेशा वकालत करता आया है. इसी वजह से भारत की हालत दो नावों में सवार सरीखी है.

न्यूयॉर्क के यहूदी गुटों ने अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सदस्य स्टीफन सोलार्ज के नेतृत्व में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से पिछले जून में मुलाकात की थी. विश्लेषकों का मत है कि इसी के बाद इस्राएल के कूटनीतिक रिश्ते फिर कायम किए गए. लेकिन रादियां इससे सहमत नहीं हैं.

लेकिन असली मोड़ पिछले साल तब आया जब काफी ऊहापोह के बाद कड़े सुरक्षा इंतजामात में इस्राएली डेविस कप टीम नई दिल्ली पहुंची थी. मगर इसके कुछ महीनों बाद भारत ने डेविस कप मैचों में तीन साल के प्रतिबंध और भारी जुर्माने के

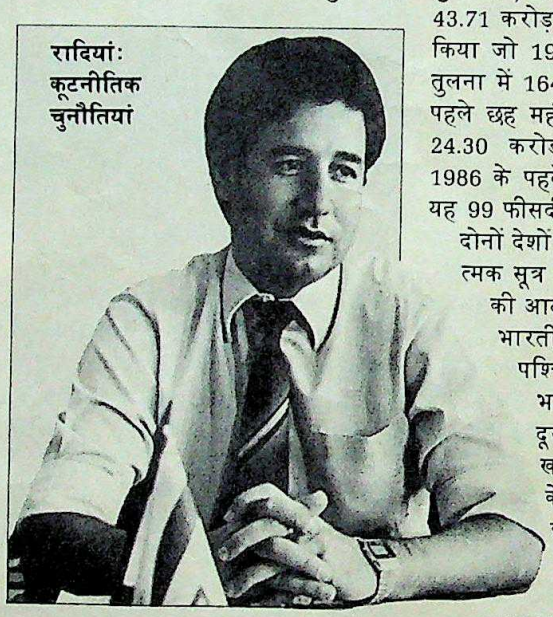

रादियां: कूटनीतिक चुनौतियां

खतरे के बावजूद इस्राएल में डेविस कप मैच खेलने से इनकार कर दिया था. रादियां कहते हैं, "हम यह नहीं मानते कि वहां खेलने में किसी तरह का खतरा था. लेकिन हमें आपके प्रधानमंत्री के इस बयान पर पूरा भरोसा है कि भारत पहले भी इस्राएल के साथ खेल चुका है और भविष्य में भी खेलने से नहीं हिचकेगा."

पाकिस्तान के एटमी इरादों से भारत जितना चिंतित है, इस्राएल भी उतना ही चिंतित है. इस्लामी देशों के गठजोड़ से यह चिंता और गहरी ही होती है. वैसे, रादियां इन अटकलों पर यकीन नहीं करते कि दिल्ली और येरुसलम के बीच इस मसले पर कोई आपसी समझदारी बनी है. चूंकि ज्यादातर विकासशील देशों ने इस्राएल का बहिष्कार कर रखा है इसलिए भारत के साथ अगर उसने रिश्ता कायम कर लिया तो यह उसकी अहम कूटनीतिक उपलब्धि ही मानी जाएगी.

इस मसले के आर्थिक पहलू भी हैं. खेती की तकनीक, श्रम संगठनों और सिंचाई आदि की व्यवस्था में प्रशिक्षण पाने के लिए भारतीय लोग 1950 से इस्राएल जाते रहे हैं. सिंचाई, विलवणीकरण, बागवानी, मुर्गीपालन, सौर ऊर्जा और चिकित्सा के क्षेत्रों में इस्राएल तकनीकी जानकारियां दे सकता है. रादियां का मानना है कि इन क्षेत्रों में दोनों देश जानकारियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार में भी इजाफा हुआ है. 1987 के पहले छह महीनों में (ताजा आंकड़ों के मुताबिक) इस्राएल ने भारत को तकरीबन 43.71 करोड़ रु. मूल्य का सामान निर्यात किया जो 1986 के पहले छह महीनों की तुलना में 164 फीसदी ज्यादा है. 1987 के पहले छह महीनों में निर्यात भी तकरीबन 24.30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. 1986 के पहले छह महीनों की तुलना में यह 99 फीसदी का इजाफा था.

दोनों देशों को जोड़ने वाले कुछ भावनात्मक सूत्र भी हैं. इस्राएल की 43 लाख की आबादी में करीब डेढ़ लाख लोग भारतीय मूल के हैं. तेजी से बदलते पश्चिम एशियाई परिदृश्य में भारत से इस्राएल की दोस्ती के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं. खाड़ी युद्ध थमने से अरब जगत के विखराव में कमी आएगी. इस्राएल के प्रति दुनिया भर की निगाहें मेहरबान-सी होने लगी हैं. गोर्बाचेव के रूस ने नामम भोजानी इस्राएल के साथ वाणिज्य-दूतों के स्तर पर कूटनीतिक संबंध बनाया है. अब यहां ज्यादा यहूदियों को प्रवास की अनुमति दी जाने लगी है. इसके अलावा पूर्वी यूरोप के दूसरे देशों ने भी इस्राएल के प्रति अपने रवैये में नरमी दिखाई है. ऐसी हालत में भारत इस्राएल और अरब जगत के बीच किसी भी समझौते में अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर इसलिए भी कि अमेरिका के शांति प्रयास नाकाम रहे हैं.

रादियां कहते हैं, "हम फिलस्तीनियों की राष्ट्रीयता के मसले पर भारतीय रवैये की कद्र करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह मुद्दा दोनों देशों के बीच आड़े नहीं आना चाहिए." अपने ही बनाए दायरों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राजनैतिक कौशल और चातुर्य की जरूरत होती है. आगामी महीनों में साफ हो जाएगा कि विदेश मंत्रालय के मंत्री-संतरी कितने पानी में हैं.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया ओनिडा.
इसे छू पाये तो बस एक ईर्षा भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्षा के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठा ले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा तशरीफ़ लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'क्यूब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' कैबिनेट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के इन्तज़ार में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्षा मंडराती है आसपास। याद रखिये वो सावधान-वाणी: अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

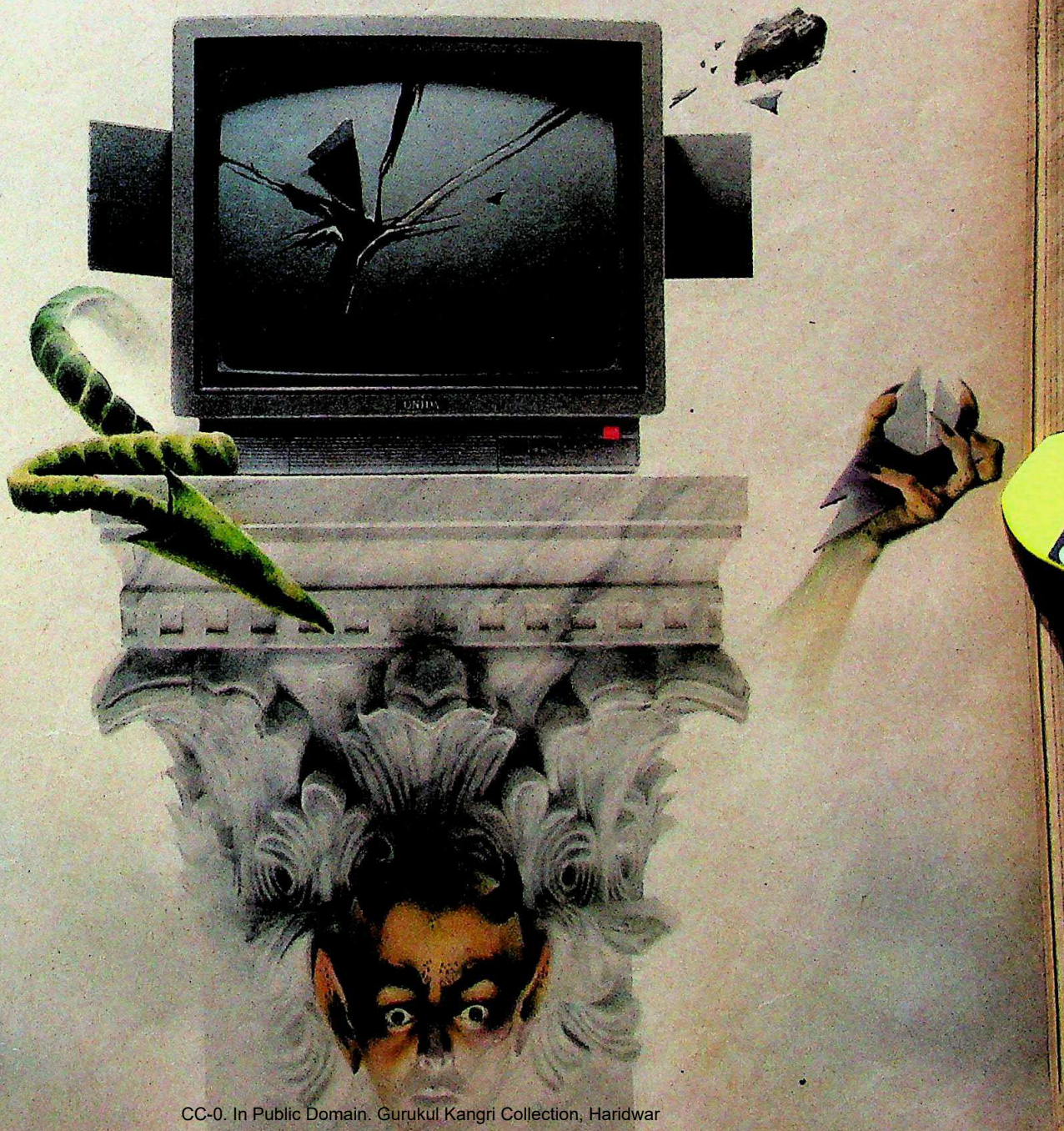

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: भवान सिंह

सिओल में भारत

मंजिल अभी कोसों दूर

खेलों के महाकुंभ में भारत फिर अपनी पुरानी कमजोरियों के साथ

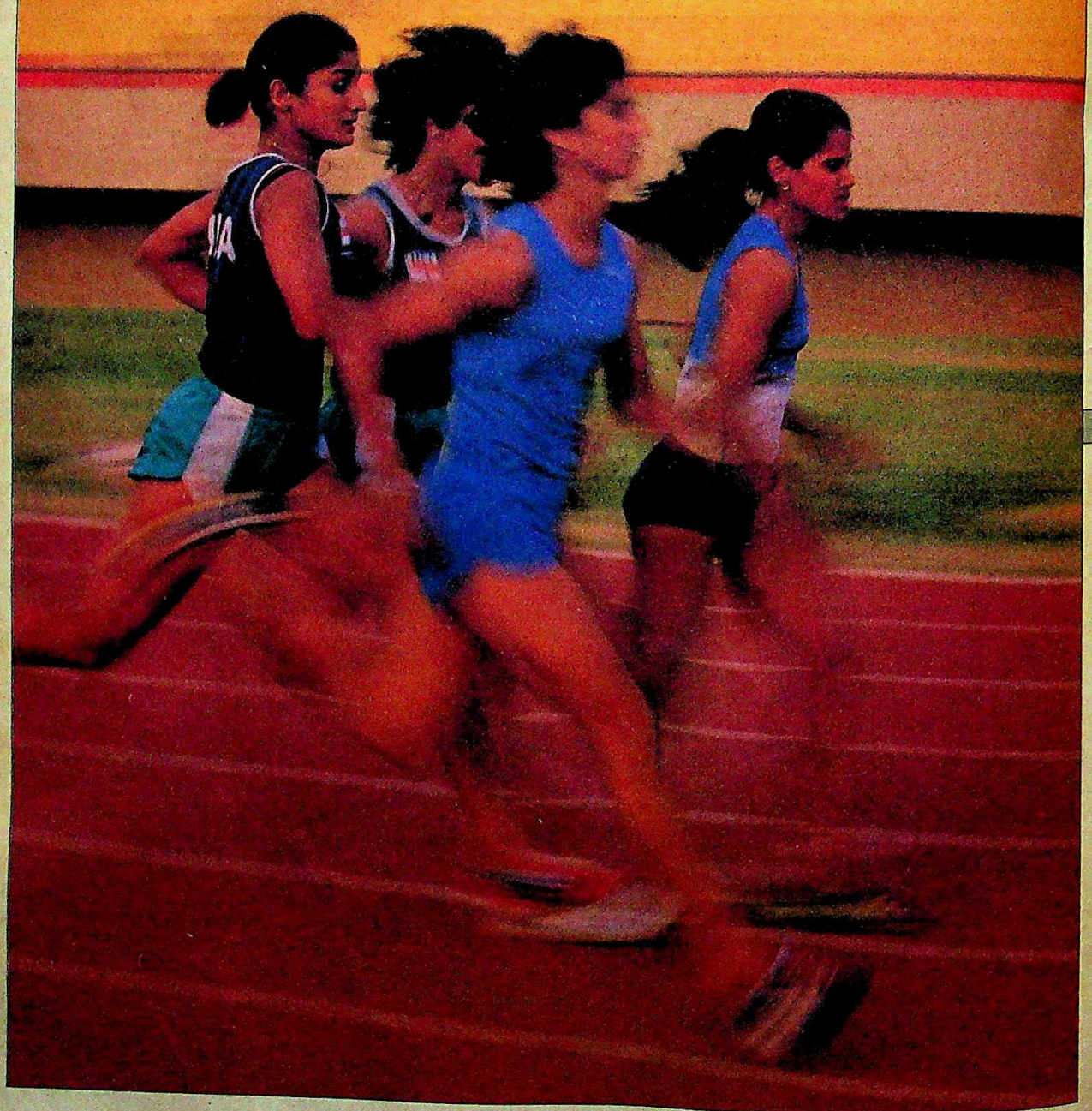

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हर चौथे वर्ष पड़ने वाले इस महाकुंभ के सामने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर होने वाली हर गतिविधि फीकी पड़ जाती है. खेलों की दुनिया की यह आखिरी मंजिल है. इसकी विशालता, इसकी संभावनाओं और शानोशौकत का कोई सानी नहीं. हर बार पहले से ज्यादा तेजी दिखती है, पहले से ज्यादा ऊंचाई, और सीमाओं को भी पार कर जाने की तमन्ना. हर चार साल बाद होने वाले ओलंपिक को देख लगता है कि मानव-रची मशीन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकी पर फिर एक कार्ल लुइस, या बॉब बीमन, या एडविन मोजेज, या कोई सर्जेई बुब्का आता है और सारे मिथक टूट जाते हैं. लेकिन 4320 करोड़ रु. के खर्च से हो रहे इस ओलंपिक से यही साबित नहीं होगा कि खेल जगत में कौन सबसे उम्दा या सबसे तेज खिलाड़ी है, बल्कि यह राष्ट्रीय गौरव की अभिव्यक्ति और विश्व मंच पर उपलब्धियों की पताकाएं फहराने का भी महती माध्यम है. आज जब उपग्रहों, माइक्रोचिप तथा जेट के युग में सरहदें बेमतलब हो गई हैं, सामाजिक मूल्य बदल गए हैं और राष्ट्रीय पहचान का तो कायाकल्प ही हो गया है, सिर्फ खेल ही किसी भी राष्ट्र की हैसियत और काबिलियत का पैमाना बनकर सामने आए हैं. इसीलिए इस पखवाड़े दुनिया के 167 मुल्क तमगों और आन-बान-शान की खोज में अपने सबसे बेहतर 30,000 स्त्री-पुरुष खिलाड़ियों को सिओल भेज रहे हैं.

1936 में ध्यानचंद और हॉकी के दूसरे महारथियों ने जब अंतरराष्ट्रीय हॉकी में भारत की महारत के झंडे गाड़े थे, उसके बाद से दुनिया काफी-कुछ सिमट चुकी है. तब ध्यानचंद के परिवारवालों को जीत की खबर पाने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ा था. लेकिन अब पांच करोड़ से भी ज्यादा भारतीय अपने-अपने घरों में बैठे एम.एम. सोमैय्या की अगुआई वाली मौजूदा टीम का कला-कौशल सीधे देख सकेंगे पर उन्हें विजय मंच या लंबे-चौड़े इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर भारतीयों की श्रेष्ठता के शायद ही कोई चिन्ह दिखें. ऐसे में वही घिसा-पिटा सवाल पूछा जाता रहेगा कि 80 करोड़ की आबादी वाला यह देश उस मंच पर क्यों नहीं है? जिस देश ने हर क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रतिभाएं दीं वह खेलों में इस स्तर तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है?

खेलों में सफलताएं किसी राष्ट्र को युद्ध के मैदान में मिली विजय की तरह ही ऊर्जा से भर देती है, और खेलों के प्रति इतने आसक्त लेकिन उसकी कीर्ति से वंचित भारत जैसे देश के लिए तो ओलंपिक के छह स्वर्ण पदक कारगर उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं. अक्सर कहा जाता है कि कोई दूसरी बात भारतीय जनता में उतनी एकता नहीं पैदा करती जितनी कि हॉकी और क्रिकेट की जीत. यहां खेलों में विजय किसी राष्ट्रीय उत्सव की तरह होती है और गौरव के उन क्षणों में सब लोग, जात-पांत, धर्म, प्रदेश, क्षेत्र के सारे भेद भूलकर एकरस हो जाते हैं.

खेलों के इतिहास की सबसे बड़ी घटना 24वें ओलंपिक की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद भारतीय खेलप्रेमी उत्साह, रोमांच और आनंदातिरेक के कुछ संतोषदायक क्षणों से गुजरने की आशा भी नहीं रख सकते. नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मैदान पर निराश-सी पी.टी. उषा शायद बड़ी पीड़ा से जॉगिंग कर रही हैं. हर बार जैसे ही उनकी पट्टियों में बंधी बाईं एड़ी जमीन का स्पर्श करती है, वे दांत-होंठ चबा लेती हैं. सिओल प्रस्थान के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रही हॉकी टीम के कप्तान सोमैय्या वादा कर रहे हैं कि "चाहे हम स्वर्ण पदक हासिल न कर पाएं लेकिन हम अच्छा खेलेंगे." टेबल टेनिस की छोटी-सी टीम अभी सदमे से नहीं उभर पाई क्योंकि उन्हें कह दिया गया है कि "जैसे ही वे

खेलों में सफलताएं किसी राष्ट्र को युद्धभूमि में मिली विजय की तरह ही ऊर्जा से भर देती हैं. खेलों में विजय राष्ट्रीय उत्सव की तरह होती है. और गौरव के उन क्षणों में लोग सारे भेद भूलकर एकरस हो जाते हैं

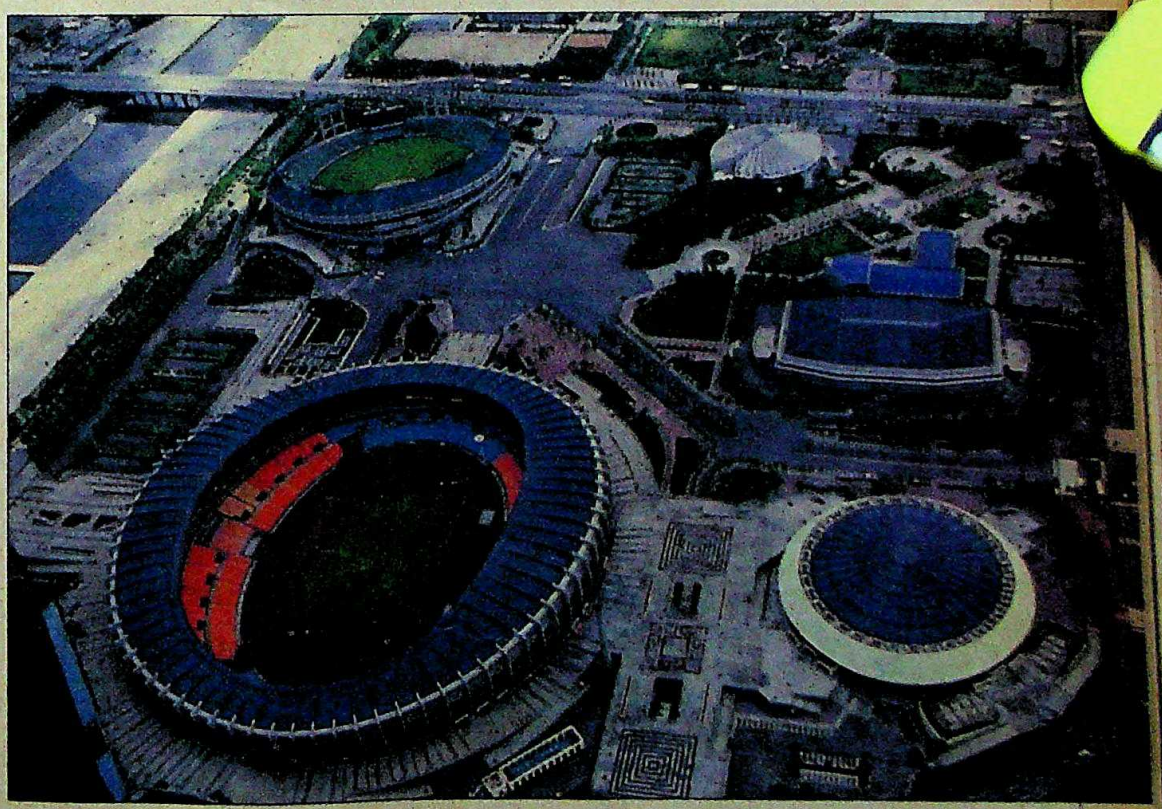

(बाएं) एशियाई रिले रेस की विजेता चौकड़ी; और सिओल का स्टेडियम

■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कलकत्ता का एक शान्त इलाका। सुबह की खुशनुमा हवा में संगीत की गूँज। उत्तर प्रेदश के बदायूँ ज़िले के नौजवान गायक राशिद खाँ अपना रियाज़ शुरू करते हैं। उन्हें विभिन्न रागों की तालीम देतेहुए उस्ताद निसार हुसैन खाँ बेहद फख़्र महसूस करते हैं और अब उन्हें पूरा यकीन है कि.प्रतिभा के फूल खिलते रहेंगे। गुरु-शिष्य के बीच ६० साल के अन्तर को इस तानपूरे ने पाट दिया, जो उस्ताद निसार हुसैन खाँ को अपने दादा से मिला था और अब उनके शागिर्द के सुनहरे भविष्य का शिल्पकार है। यह गुरु-शिष्य परम्परा की अनुपम मिसाल है। राशिद खाँ के संगीत के जादू में डूबे, उस्ताद निसार हुसैन खाँ को पिछले दशक की याद हो आती है, जब आई टी सी उनकी मदद के लिए आगे आयी...

बदायूँ के राशिद खाँ। उस्ताद निसार हुसैन खाँ परेशान थे कि उनके प्रतिभावान शागिर्द की आवाज़ दुनिया के शोर में गुम होकर रह जाएगी।

तभी आई टी सी ने संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके निराशा के अंधेरे में आशा का दीप जलाया।

ध्वनि-प्रयोगशाला में ध्वनि-शैलियों पर शोध

समुचित संरक्षण के अभाव में भारतीय शास्त्रीय संगीत मंद पड़ता जा रहा है–यह महसूस करतेहुए आई टी सी ने संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके गुरु-शिष्य परम्परा को पुर्नजीवित किया। सन् १९७८ से विभिन्न घरानों के प्रवीण संगीतज्ञ यहाँ रहतेहुए, संगीत की खिलती हुई प्रतिभाओं को तालीम दे रहे हैं।

संगीत रिसर्च अकादमी में परम्परा और तकनीक का खूबसूरत गठबंधन हुआ है। गुरु-शिष्य शिक्षा-प्रणाली के साथ-साथ यहाँ आधुनिक ध्वनि-प्रयोगशाला और ग्रंथागार भी है, जहाँ पुराने ज़माने की अमूल्य रिकॉर्डिंग संरक्षित हैं।

शास्त्रीय संगीत और नृत्य के विकास के लिए आई टी सी दिल्ली में संगीत सम्मेलन आयोजित करती है और इसी तरह अन्य शहरों में भी समारोह आयोजित किए जाते हैं। भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार का यह प्रयास, राष्ट्र के प्रति आई टी सी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मनुष्य को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य में आई टी सी के प्रयास :

कृषि उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल-बीजों के उत्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार किसानों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी ।

परिवार कल्याण : अपनी विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा आई टी सी परिवार-नियोजन के साधन आसानी से उपलब्ध कराते हुए गांव-कस्बों तक में छोटे परिवार और कई साल के अन्तर में सन्तान-प्राप्ति के लाभ का प्रचार-प्रसार कर रही है ।

कुटीर-उद्योग : शाहजहांपुर में आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के ज़रिए कालीन-बुनाइ उद्योग को पुनर्जीवित किया ताकि २५०० से भी ज्यादा परिवार बेहतर कमा सकें, बेहतर जीवन जी सकें। कालीन निर्यात द्वारा आई टी सी विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हारेंगे" उन्हें तुरंत ही लौट आना पड़ेगा.

फिर लड़कियों की रिले रेस वाली चौकड़ी है. यह चौकड़ी एक अरसे से भारत में पैदा हुए बेहतर एथलीटों में है. वे स्टेडियम के भोजन कक्ष में बैठी चाय की चुस्कियां ले लेती हैं, अपने आंसू पोछती हैं, और हर कुछ मिनट बाद वाश-बेसिन की ओर दौड़ पड़ती हैं. वे 3 मिनट 27.4 सेकंड की उस समय सीमा को छूने में नाकामयाब रही हैं जिसे खेल मंत्रालय ने मनमाने ढंग से तय कर दिया था. यह समय सीमा उनके एशियाई रिकार्ड से पूरे 4 सेकंड कम है.

कुछ घंटे बाद वे हताश-सी खेल राज्यमंत्री मार्गरेट अल्वा के सफदरजंग रोड वाले घर के आगंतुक कक्ष में बैठी दिखती हैं. अगली सुबह राजीव गांधी के सलाहकार सतीश शर्मा के दो फोन आते हैं और उनका सिओल जाना पक्का हो जाता है. यह किस्सा भारतीय खेलों की दुर्दशा का बयान करने के लिए काफी है, और यह बताने के लिए भी कि 1982 के एशियाड में खासा पैसा गलाकर जो माहौल तैयार किया गया था वह कहां हवा हो गया और पिछले पखवाड़े जब भारतीय खिलाड़ी सिओल के लिए रवाना हुए तो उम्मीद नाम की कोई चीज क्यों नहीं दिखी. दल के साथ जाने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी इसका बयान यों करते हैं, "पहले हमारे पास कुछ ऐसे खिलाड़ी होते थे जिनके फाइनल में पहुंचने की उम्मीद रहती थी. फिर हॉकी टीम के सेमी फाइनल तक न पहुंच पाने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता था. पर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो वह चमत्कार ही होगा." यह हालत बनने की वजह शायद यह है कि अफसर इन समारोहों को तफरीह का जरिया मान लेते हैं. खिलाड़ियों को भी वे इसी दृष्टिकोण से देखते हैं

उधर भारतीय ओलंपिक संघ (भाओस) के दफ्तर के गलियारों में जोड़-तोड़ करने वालों की कोई कमी नहीं थी. टेबल टेनिस फेडरेशन चाहता था कि सरकार दो प्रशिक्षकों का खर्च उठाए—मंजीत दुआ को प्रशिक्षक बनाए और इंदु पुरी को प्रशिक्षक-सह-मैनेजर. पर सरकार ने सिर्फ पुरी के लिए ही हरी झंडी दिखाई.

मुक्केबाजी महासंघ को सख्ती से कह दिया गया कि वह अपने खिलाड़ियों की संख्या पांच से घटाकर तीन कर ले. तैराक खजान सिंह टोकस को भेजने के सवाल पर भी विवाद हुआ. वे ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रशिक्षक एरिक अर्नाल्ड से प्रशिक्षण ले रहे थे. जब उसने वहां से प्रमाणपत्र भेजा कि उन्होंने निर्धारित स्तर पार कर लिया है तो कइयों की भौंहें तन गईं. अमेरिका में प्रशिक्षण ले रही निशानेबाज सोमा दत्त ने भी यही किया. एक नाराज एथलीट ने कहा, "हमारे साथ नाइंसाफी हुई. पर हमारे उन अफसरों को कौन समझाए जो दो बाधाओं के बीच की दूरी भी नहीं जानते."

भाओस के दफ्तर में जाने से ही पता चल जाता था कि भारत के खेल समुदाय में किस तरह की अशालीनता और फूहड़पन हावी है. वहां अफसरों को मुफ्त का सामान हथियाने के लिए बाटा-पावर के स्टॉल पर धावा बोलते देखा जा सकता था. अफसरों के साथ-साथ खेलों से जुड़े कई लोग यह पूछने में व्यस्त दिखाई दिए कि हांगकांग में वीडियो कितने में मिलेगा. यहां तक कि वहां नोटों को डॉलर में बदलने की पेशकश करने वाला दलाल भी घूमता दिखाई दिया.

ओलंपिक में भाग लेने वाली टीमों के अधिकारी जहां सिओल के लिए तीन-तिकड़म कर रहे थे, वहीं कुछ अनजान-से खेलों से जुड़े लोग भी पीछे नहीं थे. अल्वा कहती हैं, "यहां तो पतंगबाजी समेत हर किसी खेल का संघ

एक कड़वा सच यह है कि अगर प्रशिक्षण में कोई खामी न भी होती तो भी आज कोई भारतीय एथलीट ओलंपिक में तमगा जीत सकने की हालत में नहीं है. सिर्फ राष्ट्रीय खेल हॉकी में ही पदक की उम्मीद की जा सकती है

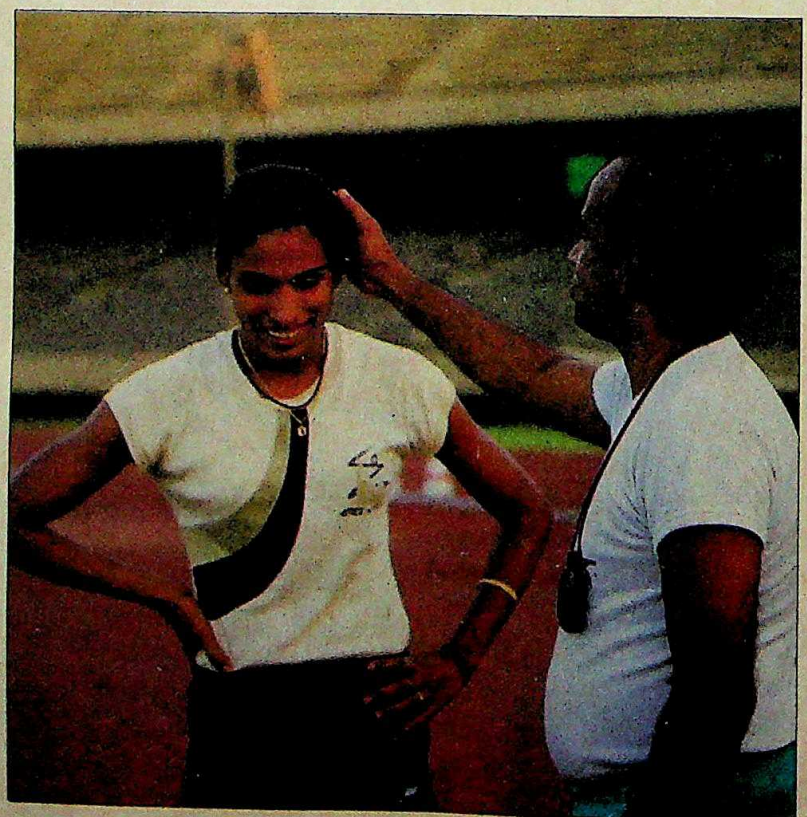

प्रशिक्षक नांबियार के साथ उषा: उपेक्षा की करुण कहानी

■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है." लेकिन वे इस बात से इनकार करती हैं कि सरकार ने जोड़-तोड़ करने वालों को सिओल भेजने की इजाजत दी. उन्होंने चुटकी ली, "आप ऐसा कुछ लिखकर तो देखिए, मैं आप पर नए मानहानि विधेयक के तहत दावा कर दूंगी." लेकिन सचाई यह है कि अफसरों ने या तो अपनी राज्य सरकारों से सिओल के टिकट का जुगाड़ किया या फिर अपनी एसोसिएशनों के सरपरस्त व्यापारियों से. फिर भाओस से उनकी एकमात्र गुजारिश यही थी कि ओलंपिक में घुसने के लिए वह उन्हें परिचयपत्र जारी कर दें. ऐसे तमाम खेलों के अलावा सरकार ने 1994 के एशियाड खेलों के आयोजन पर दिल्ली का दावा मजबूत करने के लिए एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है. इसमें 'डीडीए' के सह उपाध्यक्ष के.एस. बैंस भी हैं जो भारतीय साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष की हैसियत से गए हैं. इससे पता चलता है कि भारतीय खेलों की हालत क्या है.

पर बात यह नहीं कि भारतीय खिलाड़ी मेहनत नहीं करते. खिलाड़ियों की ताजा पौध ने तो पहले के ज्यादातर खिलाड़ियों के मुकाबले शायद कहीं ज्यादा मेहनत की है. खेल मंत्रालय और खेल संघों ने छह महीने से भी ज्यादा समय तक प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं. एथलेटिक्स और तीरंदाजी समेत कई खेलों में तो आला दर्जे के विदेशी प्रशिक्षकों से अभ्यास करवाया गया है. निशानेबाज सोमा दत्त ने अमेरिका में प्रशिक्षण लिया है और वे अमेरिकी प्रशिक्षक लेनी बाशम के साथ सिओल गई हैं. इसी तरह तैराक खजान सिंह टोकस अपने प्रशिक्षक के साथ एक अरसे से ऑस्ट्रेलिया में थे. पूरी टेबल टेनिस टीम ने चीन और जापान में प्रशिक्षण लिया है.

इसके बावजूद पदक की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि समस्याओं के कारण भारतीय खेलों का ढांचा भीतर से खोखला हो गया है. नतीजा यह है कि भारत के 76 सदस्यीय दल में सिर्फ छह एथलीट ही हैं और ये सभी लड़कियां हैं.

उषा का मामला रोगग्रस्त भारतीय खेलों की सबसे अच्छी मिसाल है. लॉस एंजिलिस में 400 मीटर की बाधा दौड़ में उसके कांस्य पदक से बाल भर पीछे रह जाने के बाद बाधाएं पार करने की उसकी तकनीक सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया. जोर इस पर दिया गया कि वह एशिया स्तर की आसान दौड़ों में शरीक होकर ज्यादा से ज्यादा पदक बटोरे. उच्च स्तर के एक एथलेटिक्स प्रशिक्षक कहते हैं, "हमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार तो नहीं डाला पर यह तय है कि हमने उसका इतना शोषण किया कि वह जो कर सकती थी उसके लायक भी नहीं रह गई."

पिछले पखवाड़े अखबारी सुर्खियों के जरिये इस त्रासदी की खबर लाखों खेलप्रेमियों तक पहुंची. उड़न सिख मिल्खा सिंह पूछते हैं, "सवाल यह है कि बड़े लोगों में से किसी ने समय रहते इसकी सुध क्यों नहीं ली?"

उषा के साथ ही भारतीय एथलेटिक्स का परचम बुलंद करने वाली दूसरी लड़कियां भी पिछले पखवाड़े उपेक्षा और आरोपों-प्रत्यारोपों का शिकार बनीं. 4 × 400 मीटर की रिले रेस में अपना एशियाई रिकार्ड सुधारने के नाम पर ये लड़कियां ओलंपिक पूर्व खेल स्पर्धा (5-6 सितंबर) तक तनाव में रहीं. अश्विनी नाचप्पा ने कहा, "अनिश्चय हमें मारे डाल दे रहा है."

तनाव और दिल्ली में फैले वायरल फ्लू के चलते यदि ये लड़कियां आखिर बीमार पड़ गईं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं. सबसे पहले बुखार ने नाचप्पा को पकड़ा. फिर जूनियर फर्राटा स्प्रिंट चैंपियन जेनिया एरटन का

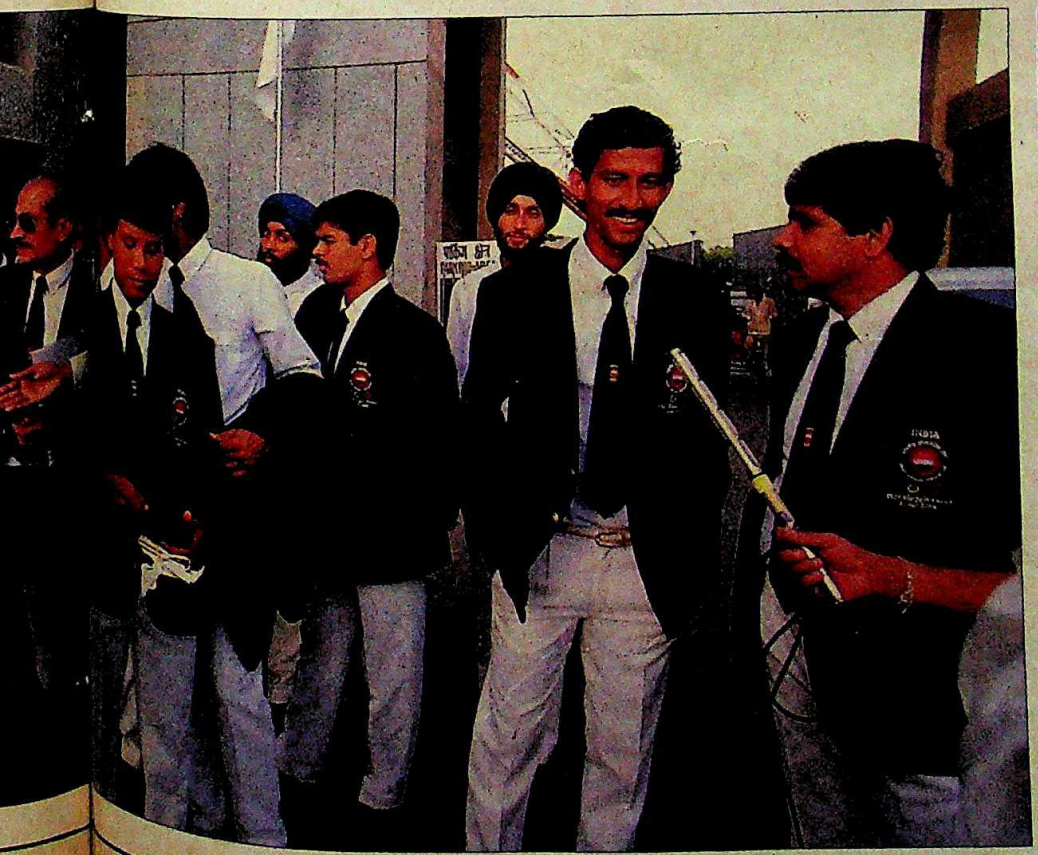

हॉकी टीम (बाएं); और तैराक खजान सिंह टोकस: स्तर में सुधार

■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नंबर आया. ओलंपिक पूर्व शिविर के दौरान वे विषाक्त भोजन का शिकार होकर बंबई लौट गई. इसके बाद वायरल बुखार ने वंदना राव को धर दबोचा. फिर शाइनी अब्राहम ने बिस्तर पकड़ लिया. बस वंदना शानबाग और मर्सी कुट्टन ही इससे बची रह सकीं.

फिर भी इन लड़कियों के जीवट की दाद देनी पड़ेगी कि तमाम परेशानियों से भरा पखवाड़ा गुजारने के बाद भी वे पूरी मेहनत से बेहतर नतीजे देने के लिए तैयार हो गईं. शाइनी कहती हैं, "भले ही हम स्वर्ण पदक नहीं जीत सकतीं पर इतना तय है कि हम एशियाई रिकार्ड तोड़ देंगी."

भारत के खेल प्रशासकों ने भी कीचड़ में कमल-सी खिलीं इन एथलेटिक्स प्रतिभाओं से तुच्छ व्यवहार किया. यह इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि किस तरह उन्होंने रिले रेस की चौकड़ी को विश्व स्तरीय टीम बनाने का मौका खो दिया. कर्नाटक की अश्विनी नाचप्पा और वंदना राव मार्च तथा मई में राष्ट्रीय खेल संस्थान, बंगलूर में हुए पहले शिविर में नहीं पहुंचीं. जब वे दूसरे शिविर के लिए पहुंचीं तो उन्हें तीन हफ्ते के लिए जर्मनी भेज दिया गया.

पर एक कड़वा सच यह है कि अगर प्रशिक्षण में कोई खामी न भी होती तो भी आज की कोई एथलीट ओलंपिक में तमगा जीत सकने की हालत में नहीं थी. इसके लिए तो सिर्फ राष्ट्रीय खेल हॉकी से ही उम्मीद है.

पिछले मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान वी. भास्करन कहते हैं, "अगर हम लीग मैचों में तीन ड्रॉ कर लेते हैं और दो जीत लेते हैं तो हम सेमी फाइनल में पहुंच सकते हैं. टीम में तजुर्बेकारों के बजाय युवा खिलाड़ी ज्यादा हैं और उनका उत्साह भारत को सेमी फाइनल में पहुंचा सकता है." हाफ लाइन के दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी और मौजूदा टीम के कप्तान सोमैय्या कहते हैं, "असल मुद्दा है सेमी फाइनल में पहुंचना. अगर हम पहुंच गए तो कुछ भी हो सकता है."

पर लीग मैचों की जो सूची बनी है उसके हिसाब से आखिरी चार में पहुंच पाना काफी टेढ़ी खीर होगा. भारत को दुनिया की सबसे मजबूत टीमों पश्चिम जर्मनी और इंग्लैंड के साथ रखा गया है. साथ ही दक्षिण कोरिया भी है जो पिछले एशियाड में भारत और पाकिस्तान दोनों को ही धूल चटा चुका है.

भारत की टीम पाकिस्तान के विरुद्ध उत्साहवर्धक मुकाबले खेलकर तरोताजा है. पर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की बेहतर टीमों के मुकाबले इसकी नवगढ़ क्षमता की आजमाइश अभी होनी है.

इसके अलावा भारत ने तीरंदाजी में भी अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है. राजस्थान की पिछड़ी मीणा जनजाति के शामलाल किसी अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं. उन्हें फरवरी में कलकत्ता में हुई एशिया कप चैंपियनशिप की 50 मीटर की प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक मिला. बाद में उन्होंने इसमें और सुधार किया और जुलाई में हुए ओलंपिक परीक्षण में उन्होंने 1440 में से 1312 अंक हासिल कर अपने को विश्व स्तरीय खिलाड़ी साबित कर दिया. इस स्कोर से तो वे पिछले एशियाड में स्वर्ण पदक जीत लेते. इसी के साथ एक और वनवासी युवक लिबाराम भी हैं. उन्हें रूसी कोच से प्रशिक्षण मिला है. वे भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना के तहत सामने आने वाले पहले महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. अगर वे ओलंपिक जैसे महाकाय आयोजन से अभिभूत न हुए और उन्होंने तीरंदाजी में हाल ही में हुई तब्दीलियों से तालमेल बिठा लिया तो वे बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं. फिर भले ही उनका निशाना किसी तमगे पर न लगे.

खुशकिस्मती से एथलेटिक्स के प्रति नौकरशाही के ओछे बरताव के मुकाबले तैराकी के प्रशासकों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. पिछले चार दशकों में देश में

खिलाड़ियों के लिए शिविर छह से ज्यादा महीने तक चले. पदक जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों के लिए तो विदेशी प्रशिक्षक तक बुलाए गए. इस तरह तीरंदाजी जैसे खेलों में भारत की शिरकत अहम साबित हो सकती है

तीरंदाज शामलाल और स्काल्जांग दोर्जे: विश्वस्तरीय प्रदर्शन

■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उभरे एकमात्र सबसे अच्छे तैराक के नाम को ओलंपिक के लिए हरी झंडी दिखाने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई. दिल्ली के पुलिस-वाले खजान सिंह ने 1982 के एशियाई खेलों के बाद से अपने प्रदर्शन में जोरदार सुधार किया है. तैयारी शिविर में उन्होंने एरिक अर्नाल्ड से प्रशिक्षण लिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में उनकी अकादमी में चले गए. उन्होंने अपने प्रदर्शन में 13 सेकंड तक का सुधार किया और सिओल एशियाड की 200 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक हासिल किया. 1951 के पहले एशियाई खेलों के बाद से भारत द्वारा तैराकी में जीता गया यह पहला पदक है. पर सिओल में पहुंचे उम्दा तैराकों के मुकाबले खजान सिंह की कोई बिसात नहीं है. लेकिन उत्साह और अनुभव के बल पर वे पेइचिंग एशियाड तक नई बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं.

एथलेटिक्स, हॉकी, तैराकी और तीरंदाजी के अलावा भारत मुक्केबाजी, निशानेबाजी, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती और नौकायन में भी भाग ले रहा है. पर अगर कुश्ती के पहलवानों में से किसी ने कोई चमत्कार न कर दिखाया तो तय है कि सबको निराशा ही हाथ लगेगी. टेबल टेनिस टीम की प्रशिक्षक, मैनेजर तथा आठ बार राष्ट्रीय महिला चैंपियन रह चुकीं इंदु पुरी जैसे सचाई ही कबूल करती हैं, "हमारी प्रतिभाओं का आधार बहुत छोटा है. दक्षिण कोरिया जैसे देशों की विश्वविद्यालय स्तर की टीम हमारी राष्ट्रीय टीम को हरा देगी. उनकी स्कूली टीम भी हमें नाकों चने चबवा सकती है."

तमगों की उम्मीद भले ही कमजोर हो या सिरे से ही गायब हो पर पिछले पखवाड़े सिओल जाने वाली औरतों और मर्दों के चेहरे उल्लास से दमक रहे थे. वंदना शानबाग

एथलेटिक्स

भविष्य अंधकारमय नहीं

भारतीय खेल जगत '70 और '80 के दशक के चुक गए खिलाड़ियों की जगह हालांकि नए चैंपियन पैदा करने में नाकाम रहा है, फिर भी उसका भविष्य इतना अंधकारमय नहीं है. शायद टेनिस और बैडमिंटन को छोड़ लगभग हर क्षेत्र में होनहार युवा खिलाड़ी हैं. अगर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाए तो भारतीय खेलप्रेमियों के लिए '90 का दशक ज्यादा आनंदमय होगा.

सबसे अच्छी संभावनाएं ट्रैक ऐंड फील्ड में देखी जा रही हैं. राष्ट्रीय कोच जे.एस. सैनी कहते हैं, "हो सकता है खिलाड़ियों का अभाव जल्दी ही खत्म हो जाए." आने वाले वर्षों में औरों के अलावा चार नाम सुर्खियों में आ सकते हैं. ये हैं:

जेनिया एरटन (फर्राटा दौड़): मास्टर्स प्रतियोगिता में सेनी जोसफ से हारने के बाद इस धाविका की श्रेष्ठता को थोड़ी आंच पहुंची है. दौड़ के प्रथम 50 मीटर तक वे जोसफ से आगे थीं. लेकिन 15 साल की उम्र में उन्होंने 12.18 सेकंड का जो रिकार्ड बनाया है, फिलहाल किसी भारतीय लड़की में उसे तोड़ने की क्षमता नहीं दिखती. जेनिया के प्रशिक्षक आदिल सुमारीवाला हैं जो खुद कई वर्षों तक भारत के सबसे तेज धावक रहे. वे कहते हैं, "जेनिया से हमें बहुत आशाएं हैं. उसके पास गजब की प्रतिभा है. पर हमें उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए." वे उसे कड़ा प्रशिक्षण देते हैं. जेनिया कहती हैं, "मैं शिखर पर पहुंचना चाहती हूं. और पहुंचूंगी भी जरूर, इसमें कोई शक नहीं."

जेनिया और (नीचे बाएं से) इकबाल तथा एजेंला: आशा केंद्र

प्रदीप मधानी

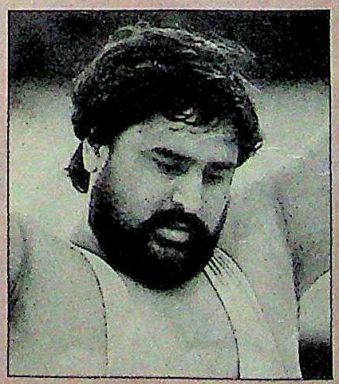

प्रदीप मधानी

एंजेला लिसी (ऊंची कूद): जेनिया की तरह 17 वर्षीया लिसी में भी '80 के दशक की उस परंपरा को जीवित रखने की क्षमता दिखाई पड़ रही है जब दौड़ के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं का प्रभुत्व था. यह छात्रा 1.73 मीटर ऊंची कूद का राष्ट्रीय रिकार्ड पहले ही बना चुकी है. अभी भी टांगें फैलाकर कूदने की पुरानी शैली का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन उनके प्रशिक्षक अब कोशिश कर रहे हैं कि वे 'फॉस्बरी फ्लॉप' शैली अपनाएं. वे कहती हैं, "पेइचिंग में मैं एक पदक जरूर हासिल करूंगी. तब तक मैं 1.90 मीटर तक ऊंची कूद लगाने में सक्षम हो जाऊंगी."

शाइनी वर्गीज (भाला क्षेपण): दक्षिण की यह एक और उभरती खिलाड़ी है. रूसी कोच अलेक्सी पोपोव के प्रशिक्षण में उनके प्रदर्शन में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है. विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भाला फेंकने के क्षेत्र में एक दिन जरूर ऊंचाई पर पहुंचेंगी. 18 वर्षीया शाइनी 51.88 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकार्ड बना चुकी हैं. वे कहती हैं, "शिखर पर पहुंचने के लिए मेरे पास शक्ति, योग्यता और इच्छा है."

24 वर्षीय इकबाल सिंह ने ओलंपिक पूर्व प्रतिस्पर्धा में 18.77 मीटर तक गोला फेंकने में सफलता पाई. वे मेहनती हैं और इस क्षेत्र में भारत के अच्छे प्रदर्शन की परंपरा को पुनर्जीवित कर सकते हैं. सिओल जाने के लिए आखिरी क्षण तक जूझने वाले इकबाल ने कहा, "मेरे बारे में खुद मेरा रिकार्ड ही कहता है."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

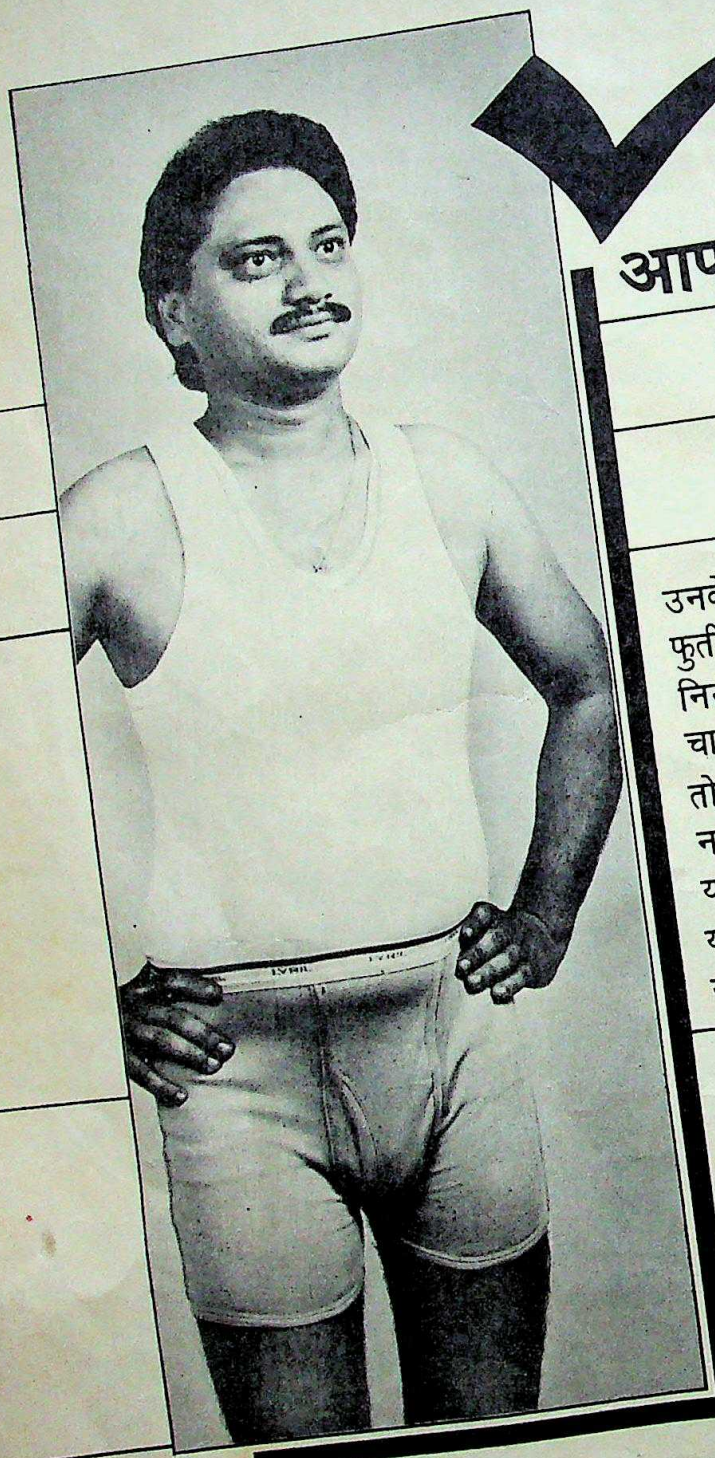

आप जैसे जवां मर्द के लिये

उनके लिए जो तेज तर्रार हैं
फुर्तीले हैं प्रगतिशील है.....
निरंतर समय के साथ-साथ चलना
चाहते हैं हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हैं
तो लीजिए – लिरिल की सौगात
नयी पीढ़ी की नयी पसंद
यह खूबसूरत है.....
यह मजबूत है यह टिकाऊ है
यह कई रंगों में मिलती है

लिरिल

- अंडरवियर
- बनियान

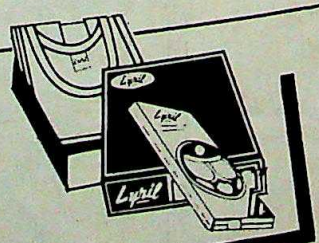

ATUL PUBLICITY

Lyril®

चुस्त फुर्तीले मर्दों
की पहली पसंद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहती हैं, "ओलंपिक में भाग लेना ही क्या अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है?" महीनों और वर्षों की मेहनत-मशक्कत के बाद ओलंपिक में भाग लेने की उम्मीदें संजोने वालों को आखिरकार जाने का मौका मिल रहा है लेकिन वहां वे सिर्फ देशभक्ति के गीत गाने का ही काम अंजाम देंगे.

शुरू में सारा झंझट इसलिए हुआ कि एक हाथ को पता नहीं था कि दूसरा क्या कर रहा है. अचानक दूसरे दर्जे के टिकटों के साथ ही खिलाड़ियों के पास तार पहुंचे जिनमें कहा गया था कि सिओल के लिए गये शिविर में हाजिर हों. उनके पहुंचने के कुछ दिन बाद तक किसी को मालूम नहीं था कि इस 'सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल' का आखिर किया क्या जाएगा. अंततः जब उनका ज्ञानवर्धन किया गया कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तो कुछ ने सोच लिया कि बेहतर तो यह होता कि उन्हें भविष्य की स्पर्धाओं के लिए तैयार किया जाता. बहरहाल, छिद्रान्वेषी लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया है कि सिओल में भारत की तरफ से सबसे बेहतर प्रदर्शन तो ये हाजिरी बजाने वाले ही करेंगे. यानी 1988 में खेल जगत में चरम प्रसिद्धि पाने के इस महाकुंभ में भारत इसी संदेश के साथ सम्मिलित हो रहा है.

—**शेखर गुप्ता** और **डेविड देवदास,**
साथ में **अमरनाथ के.मेनन** व ब्यूरो रिपोर्टें

भारतीय खेल

राह के रोड़े कैसे हटें

दीर्घकालिक योजना बनाने और गुदड़ी के लाल ढूंढ़ने की जरूरत

भारतीय खेलों की दशा सुधारना किसी उलझे महाजाल को सुलझाने की तरह ही है— एक गांठ सुलझी नहीं कि पांच और गांठें उभर आती हैं. 'इंडिया टुडे' ने देश भर के अनेक प्रशिक्षकों, वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों से बातचीत कर इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की है कि भारतीय खेलों की मंजिले मकसूद की राह में पड़े रोड़ों को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है:

पिछले पूरे एक पखवाड़े तक प्रचारित किया जाता रहा कि इन एथलीट स्पर्धाओं में दुनिया के नामी खिलाड़ी आ रहे हैं. वे आए और उन्होंने दिल्ली में हुई ओलंपिक पूर्व स्पर्धा में कीर्ति पताकाएं फहराईं. लेकिन यह प्रतियोगिता कई मायनों में आंख खोलने वाली भी साबित हुई और हौसला अफजाई करने वाली भी.बड़े खिलाड़ियों की संगत पाकर, उनसे प्रेरणा लेकर कम-से-कम पांच भारतीय एथलीटों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिखाया. लेकिन वे औसत दर्जे के विदेशी खिलाड़ियों से भी पीछे ही दिखे.

भारत में कुछ खेलों के रिकॉर्ड लंबे समय से बरकरार रहे हैं. पुरुषों की कुछ फर्राटा और मध्यम दूरी की दौड़ों के रिकॉर्ड तो एक दशक से भी ज्यादा समय से टूटे नहीं. यहां तक कि उन्हें कोई गंभीर चुनौती भी नहीं मिली. इसी तरह हॉकी को छोड़कर टीम वाले खेलों में भी भारत का स्तर गिरता गया है. छोटी दूरी की तेज दौड़ के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन आदिल सुमारीवाला कहते हैं, " आपने सवाल किया है कि भारतीय खेलों के साथ गड़बड़ी क्या है? जरा आप ही बताइए उसकी दशा ठीक कहां है?" वे फिलहाल छोटी दूरी की तेज दौड़ की युवा एथलीट जेनिया एरटन के प्रशिक्षक हैं.

विशेषज्ञों की आम राय है कि भारतीय खिलाड़ियों को कुछ मूलभूत असुविधाएं झेलनी पड़ती हैं. मध्यम दूरी की दौड़ में एशिया में अब तक के सबसे तेज धावकों में

दिल्ली में हुई ओलंपिक पूर्व प्रतिस्पर्धा में बड़े खिलाड़ियों से प्रेरणा पाकर पांच भारतीय एथलीटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो जरूर किया मगर वे औसत दर्जे के विदेशी खिलाड़ियों से पीछे ही दिखे

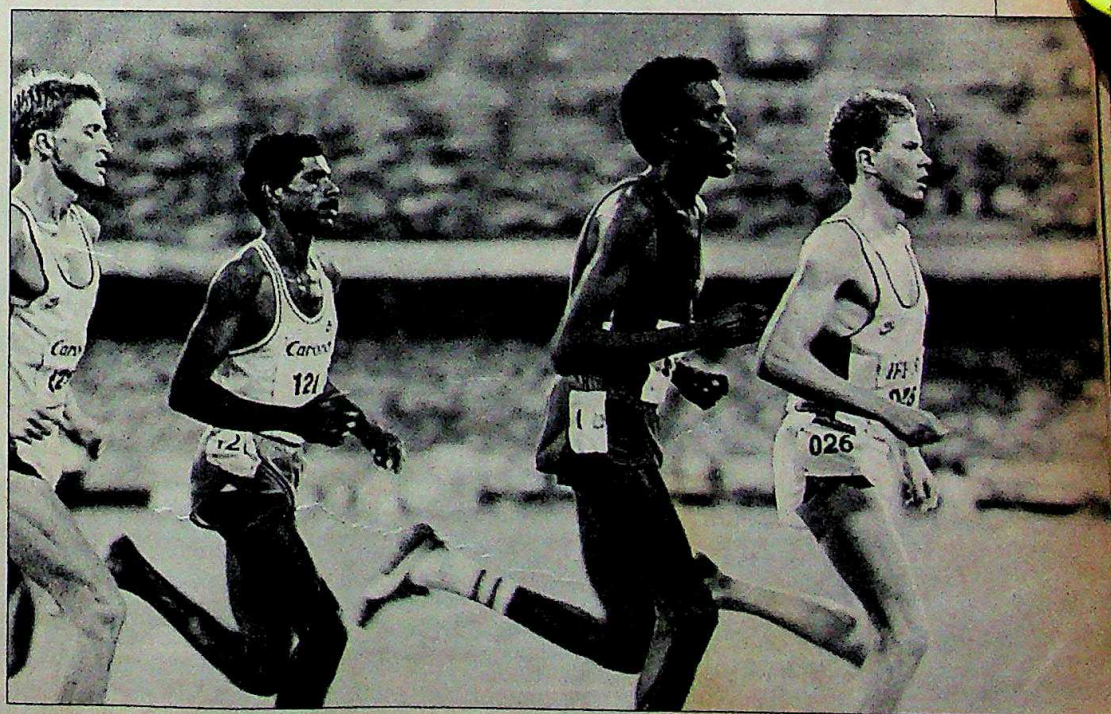

दिल्ली की ओलंपिक पूर्व प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते एथलीट

■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शुमार श्रीराम सिंह खिन्न मन से कहते हैं, "यहां गरीबी है, पौष्टिक आहार का अभाव है और अभिभावक भी खेल के प्रति उचित रवैया नहीं अपनाते. ऐसी स्थिति में आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं?" मगर चक्का फेंक के राष्ट्रीय चैंपियन, 23 वर्षीय शक्ति सिंह इतने हताश नहीं हैं. वे कुछ आशान्वित दिखते हैं, "हम जैसा चाहते हैं वैसा भोजन हमें साल भर तक दीजिए और तब हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए." वे सिओल ओलंपिक में शरीक होने तो नहीं जा रहे हैं पर 1990 के पेइचिंग एशियाड में स्वर्ण पदक जरूर हासिल करने का हौसला रखते हैं.

लेकिन इन सबके बावजूद भारत में समय-समय पर ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर सामने आते ही रहे हैं जो अपनी प्रतिभा के बूते इन सब बाधाओं को पार करने में कामयाब रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय खेल मंच. पर भारत की मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे हैं. बिलियर्ड में गीत

मार्गरेट अल्वा

'सिओल हमारा लक्ष्य नहीं'

सिओल ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की अगुआई करना खेल, महिला और युवा मामलों की केंद्रीय राज्यमंत्री मार्गरेट अल्वा के लिए जोखिम भरा काम है. भारतीय दल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद न होने से जाहिर है इसका कुछ दोष अल्वा के मत्थे भी आएगा. लेकिन फीचर संपादक ***शेखर गुप्ता*** *और वरिष्ठ संवाददाता* ***डेविड देवदास*** *से एक घंटे की बातचीत में वे आशावान ही दिखीं. इस बातचीत के कुछ अंश:*

● ***सिओल ओलंपिक के पहले कैसे मिजाज हैं?***

मैं निराशावादी कतई नहीं हूं. सिओल में हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी भले ही न दिखती हों पर हम सही रास्ते पर हैं.

● ***यह आप कैसे कह सकती हैं? वह भी जब एशियाड की सारी सुविधाओं के बावजूद हमारे खेलों के स्तर में भारी गिरावट आई है.***

खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं तो 1982 में हासिल हुईं, वह भी सिर्फ दिल्ली में. पर खेलों के बारे में नया सोच तो 1985 से ही बना. बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए अचानक धन भी उपलब्ध होने लगा तो हमने 1990 में चीन में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 'ऑपरेशन एक्सेलेंस' शुरू कर दिया. सिओल तो कतई हमारा लक्ष्य नहीं था.

● ***चीन और दक्षिणी कोरिया ने खेलों में इधर नई महारत हासिल की है. क्या हमने इन नए महारथियों से कुछ सीखा है?***

आप दक्षिण कोरिया की बात करते हैं. उन्होंने अपने समस्त ओलंपिक खिलाड़ियों को पूरे एक साल के लिए सैनिक कमांडो के हवाले कर दिया था ताकि उनमें अनुशासन आए और जीत की प्रबल इच्छा हिलोरें ले. यहां तो आलम यह है कि सेना के लोग भी अपने खिलाड़ियों को शिविरों में नहीं भेजते. इंडियन एअरलाइंस का भी यही हाल है. हमें अपनी ही प्रणाली ईजाद करनी पड़ी.

● ***क्या आपका मुख्य लक्ष्य पेइचिंग एशियाड में बेहतर नतीजे लाना है या कोई दूरगामी उपलब्धि हासिल करना?***

हम बुनियादी तब्दीलियां ला रहे हैं. हमारा पहला कदम खेलों को समवर्ती सूची में शामिल करना रहा. हमने 25 देशों के कानूनों का अध्ययन किया है. एक भी ऐसा देश नहीं जहां खेल संघ केंद्रीय सरकार के कानून के तहत गठित न हों. हमारे देश में ही स्वायत्तता की आड़ में ऐसा नहीं होता. अब हम भी उसी तरह का कानून ला रहे हैं जिससे हमें खेलों को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. पहले लोग आकर कहते थे कि "जापान में नौका दौड़ के लिए मेरे पास मुफ्त के टिकट हैं. इसलिए वहां जाने की अनुमति दी जाए." तब न तो समुचित प्रशिक्षण था और न ही चयन प्रणाली. लेकिन अब यह किसी की बपौती नहीं रह गई है. मैं रहूं या न रहूं पर आप 1990 तक इसका नतीजा देख लेंगे.

● ***क्या आपको पता है कि खेलों में राजनीति चलती है और इनका प्रबंधन भी बहुत स्तरीय नहीं है?***

इसमें कुछ बदलाव तो होगा. सबसे पहले हम चाहते हैं कि पैसे का उचित प्रयोग हो. पहले हम नई बुनियादी सुविधाओं के लिए ढाई लाख रु. तक का अनुदान दिया करते थे. लेकिन बहुत खर्चीले शिलान्यासों को छोड़ कुछ भी नहीं हुआ. अब हमें जब तक किसी परियोजना के पूरा होने का प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा, राज्यों को अनुदान नहीं दिया जाएगा.

● ***लेकिन जिस तरह का व्यवहार हम अपने खिलाड़ियों के साथ करते हैं, क्या उन पर इसका असर नहीं पड़ता? आपको पता है चैंपियन खिलाड़ियों तक को वीआईपी लोगों के चरण छूने के लिए मजबूर किया जाता है?***

यह तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है. लेकिन कुश्ती में तो गुरु और बड़े लोगों के चरण

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...ठी या माइकल फेरेरा, शतरंज में विश्व-...नाथन आनंद, ब्रिज (ताश का खेल) के ...बसे कम उम्र के विश्व चैंपियन जैगी ...विदसानी वगैरह अपने व्यक्तिगत प्रयासों ...और खेल में रुचि के कारण ये बाधाएं लांघ ...पाए और शीर्ष तक पहुंचने में सफल रहे. ...इनके अलावा पी.टी. उषा, श्रीराम सिंह, मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह रंधावा और प्रकाश पादुकोणे भी हैं. लेकिन ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जिन्हें मदद की जरूरत है. खेलों के मामले में आज भारत के अव्वल राज्य केरल के खेल परिषद के अध्यक्ष वी.जी. गोविंदन नायर कहते हैं, "हमारे देश के खेल प्रशासन में भी पेरेस्त्रोइका (आमूल बदलाव) की जरूरत है."

सबसे पहले तो भारत को आनन-फानन में पदक प्राप्त करने की धुन और विजय मंच पर न चढ़ पाने के कारण उपजता ग्लानि का भाव कम करना है. यह तो ऐसा ही है जैसे आप किसी बेहद ढलवां पिरामिड पर चढ़ने की कोशिश करें, बिना मजबूत आधार बनाए. ऐसे में हताशा और ग्लानि तो झेलने पड़ेगी. सिओल रवाना होने के ठीक पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के.पी. सिंहदेव ने इस तथ्य को जैसे स्वीकार भी किया, "कुल मिलाकर हमारी समस्या यही है कि हमारे प्रतिभा रूपी पिरामिड का आधार बहुत ही संकरा है."

इसे कोई पसंद करे या न करे, पर देश ने खेल में उपलब्धि की सीढ़ी के सबसे ऊपरी सिरे से निवेश करना शुरू किया है. पिछले छह साल में दिल्ली और आधे दर्जन दूसरे शहरों (जैसे पटियाला, बंगलूर और गांधीनगर वगैरह) में विश्व स्तर के स्टेडियम तैयार कर दिए गए और खेल के दूसरे आधुनिक उपकरण भी जुटा लिए गए हैं. राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में चैंपियन होने वाले एथलीटों के शिविर लगाए जाते हैं, उन्हें विदेशों में भेजा जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और यहां तक कि तमाम तरह के उपकरण भी मुहैया कराए जाते हैं.

लेकिन सचाई तो यही है कि लंबी अवधि की उपलब्धियां इन सुविधाओं को कस्बों के स्तर पर मुहैया कराने से ही हासिल हो सकती हैं. नई योजनाओं के तहत ऐसा कुछ हद तक हुआ भी है. इन योजनाओं के जरिये गुदड़ी के लाल ढूंढ़ निकाले गए हैं, पिछड़े माने जाने वाले इलाकों से युवा खेल प्रतिभाएं सामने आई हैं. अब इन्हें विश्व स्तर पर हर रिकार्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी पैदा करने की आशा से उन्हें खास-खास तरह

...की परंपरा पुरानी है. अभी उस दिन ...में दिल्ली में गुरु हनुमान के अखाड़े पर ...थी तो उन्होंने सभी पहलवानों को ...बुलाकर मेरे पैर छूने को कहा. मैंने कहा, ...क्या यह सब क्या है? मेरे बच्चे तक ...मेरे पैर नहीं छूते. और यहां ये हृष्ट-पुष्ट ...मेरे पैर छू रहे थे. ताज्जुब है!

• क्या यह सच नहीं कि पारंपरिक सामाजिक बंधनों और आहार से हमारे खिलाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है?

सामाजिक स्थिति बदल रही है. हम ...लते हैं कि डील-डौल के मामले में ...ज्यादातर भारतीय उतने मजबूत नहीं ...जितने कुछ दूसरे देशों के लोग. लेकिन हमें ...न कुछ अपने तरीके से बदलना होगा. हम ...सी खिलाड़ियों को अचानक मांसाहारी ...ी बना सकते. हमने पटियाला में जिस ...ंगी कोच को रखा, वह चाहता था कि ...शिक्षणार्थी सुबह के नाश्ते में सॉसेज, ...पहर के खाने में ठंडा मांस और रात में ...ला हुआ मांस खाएं. प्रशिक्षणार्थियों को ...ह अपमानजनक लगा.

• लेकिन शिविरों में जो कुछ मिलता है, उससे कहीं बेहतर और ज्यादा संतुलित आहार तो हम उन्हें दे ही सकते हैं.

दिल्ली के शिविर से खाने के बारे में ...कायतें मिली थीं, सो हमने ठेकेदार को ...दल दिया. लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं ...उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. ...पलन, उत्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए ...ब बंगलूर जाते हैं तो उन्हें वहां थोड़ा-...हुत दक्षिणी खाना मिलेगा ही. वे हर समय ...ह शिकायत नहीं कर सकते कि उन्हें ...र्याप्त लस्सी और मक्खन नहीं मिलता. मैं ...उन्हें हमेशा दिन में मखनी चिकन और रात ...में तंदूरी चिकन नहीं दे सकती.

• क्या आप यह भी मानती हैं कि हमारे खेलों की एक सबसे बड़ी समस्या मनोबल की कमी है?

बिलकुल. मनोबल तो है ही नहीं. हम ...शकूक हैं. यहां कई तरह की सनकें हैं. हमने ...जीत के लिए कीमत अदा करना सचमुच ...ही सीखा.

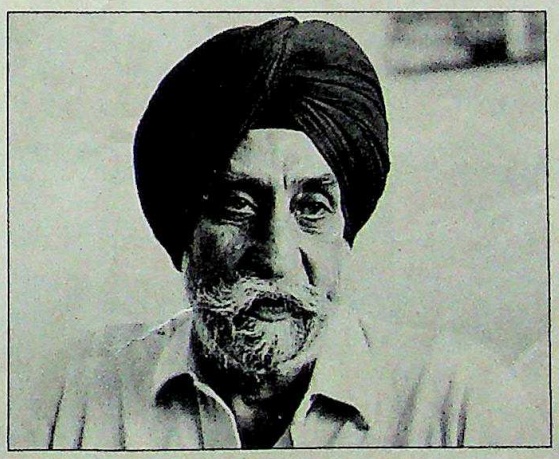

"छह साल पहले 54 सेकंड से कम में 400 मीटर की दौड़ पूरी करने वाली दो लड़कियां थीं. अब 53 सेकंड वाली पांच हैं"

जे.एस. सैनी
एथलेटिक्स के राष्ट्रीय प्रशिक्षक

■

"हमारी समस्या यही है कि हमारे प्रतिभा रूपी पिरामिड का आधार बहुत संकरा है. इसे निश्चित रूप से व्यापक किया जाना चाहिए"

के.पी. सिंहदेव
सिओल में भारतीय दल के नेता

■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के खेलों का जबरदस्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

यह तमाम जद्दोजहद बेकार नहीं गई है. इसके कारण कुछ युवा प्रतिभाएं वाकई उभरी भी हैं. एथलेटिक्स के राष्ट्रीय प्रशिक्षक जे.एस. सैनी कहते हैं, "अब आप जरा ट्रैक पर नजर तो दौड़ाइए. पूरा परिदृश्य कितना कुछ बदल गया है. छह साल पहले हमारे पास 54 सेकंड से कम समय में 400 मीटर की दौड़ पूरी करने वाली सिर्फ दो लड़कियां ही थीं. अब लगभग 53 सेकंड में यह दौड़ पूरी करने वाली कम-से-कम पांच लड़कियां हैं." उनका कहना है कि भारत का मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ पर 'पारंपरिक कब्जा' रहा है. उम्मीद है वह यह 'कब्जा' फिर से हासिल कर लेगा.

भारत आज अगर एथलेटिक्स में फिर से पांव जमाने लगा है, तो उधर एक एकदम नए खेल में भी मुट्ठी भर युवा खिलाड़ी सीधे शिखर पर पहुंचने की उम्मीदें जगा रहे हैं. इस खेल में उसकी शिरकत नई बात है. यह खेल तीरंदाजी है. हमारे दो युवा तीरंदाज विश्व स्तर के हैं और उन्हें बड़ी सावधानी और जतन से विकसित करने की जरूरत है.

टेबल टेनिस और साथ ही लॉन टेनिस में भी नए खिलाड़ियों की अच्छी और संभावनाओं से भरपूर पौध उभरकर सामने आ रही है. वनवासी लड़कों की हॉकी टीम भी इतनी तेजी से तैयार हो रही है कि इसके हट्टे-कट्टे और एकदम चुस्त-दुरुस्त दो या तीन वनवासी युवक जल्दी ही राष्ट्रीय टीम में स्थान पा सकते हैं. लंबी कूद के पूर्व चैंपियन सुरेश बाबू कहते हैं, "यदि हम पेइचिंग एशियाड के लिए प्रशिक्षण जारी रखें और इसी क्रम में 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक पर निगाह रखें तो हम इस पर्याप्त समय में ऐसे खिलाड़ी जरूर तैयार कर सकते हैं जो पदक बटोर लाने में सक्षम हों."

लेकिन असल योजना तो वही होगी जिसमें गांव और कस्बों के स्तर से खेल प्रतिभाओं को ढूंढ़ निकाला जाए और अपने आप सामने आने वाले चुनिंदा संभावित खिलाड़ियों को चुनने के बजाय ये सुविधाएं आम जनता को मुहैया कराई जाएं. राष्ट्रीय खेल संघों के महासंघ के अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा कहते हैं, "लाखों लोगों को खेल के मैदान तक लाना चाहिए. इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे खिलाड़ी उभरेंगे जो विश्व स्तर के खिलाड़ियों को मात देने में कामयाब हो सकेंगे."

फिलहाल तो दशा यह है कि देश के 90 फीसदी प्राथमिक स्कूलों में खेल के ठीकठाक मैदान तक नहीं हैं और किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होने वाले खेल उपकरण नहीं हैं. मल्होत्रा बताते हैं, "भारत में अभी एस्ट्रो टर्फ लगे हॉकी के मैदान तीन ही हैं जबकि हालैंड में ऐसे मैदानों की संख्या 300 है."

टेबल टेनिस की पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी इंदु पुरी कहती हैं, "हम सिर्फ दीर्घावधि की योजनाओं से ही कुछ हासिल कर सकते हैं. इसका सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि सभी पूर्व चैंपियनों को प्रशिक्षण के काम में लगा दिया जाए." ऐसा कुछ तो हो भी रहा है. हाल ही में खेलों से अवकाश लेने वाले कई खिलाड़ियों को नए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के काम में लगा दिया गया है. देश भर में नई संरचना, स्टेडियम और जिम्नेजियम के अलावा कुश्ती के अनेक अखाड़े भी तैयार किए जा रहे हैं.

खेल राज्यमंत्री मार्गरेट अल्वा मानती हैं कि राजनीति, अधिकारियों की उठापटक और अव्यवस्था जैसी मुख्य समस्याएं रातोरात समाप्त नहीं हो सकती. लेकिन वे वायदा करती हैं कि अब सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्रतिभाएं नष्ट न होने दी जाएं. भारतीय खेल प्राधिकरण युवा प्रतिभाओं को ढूंढ निकालने के जबरदस्त प्रयत्न कर रहा है और उन्हें विकसित करने के लिए देश भर में खेल के विशेष स्कूल और प्रतिभा केंद्र स्थापित कर रहा है.

यदि ये सारे कार्यक्रम इसी गति से जारी रहे और पारंपरिक विशेषता प्राप्त करने के लिए प्रतिभाओं का पोषण होता रहा तो कोई कारण नहीं कि हॉकी के अलावा दूसरे खेलों में भी भारत को ओलंपिक में कोई पदक न हासिल हो सके.

खेलों के विकास की नई जद्दोजहद बेकार भी नहीं गई है. इसके कारण कुछ युवा प्रतिभाएं वाकई उभरी भी हैं. ये मुट्ठी भर युवा खिलाड़ी शिखर पर पहुंचने की उम्मीदें जगा रहे हैं. जरूरत उन्हें जतन से विकसित करने की है

भवान सिंह

प्रशिक्षण शिविर की समाप्ति पर मार्च करते खिलाड़ी

■

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वित्तीय संस्थाओं के तीखे तेवर

जहां मोदी रबर में मोदी घराने के विभिन्न धड़ों की लड़ाई अब अदालत में चली गई है, वहीं यह लगता है कि वित्तीय संस्थाएं टायर कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही हैं. संस्थाओं के 42 फीसदी शेयर हैं पर बताया जाता है कि बाजार से शेयर खरीदकर वे अब करीब 49 फीसदी शेयरों की स्वामी बन गई हैं. इन संस्थाओं ने कंपनी के 16 सदस्यीय बोर्ड में अपने तीन और व्यक्ति नामजद करके अपने सदस्यों की संख्या छह तक बढ़ा ली है. संस्थापक गूजरमल मोदी के पांच बेटों ने इस पर आपत्ति उठाई. उन्होंने इन संस्थाओं के साथ मोदी रबर के हुए कर्ज समझौते की एक धारा को उद्धृत किया जिसके तहत ये संस्थाएं अपने तीन प्रतिनिधि से ज्यादा नहीं रख सकतीं. लेकिन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मोदी रबर के प्रबंध निदेशक बी.के. मोदी को एक चिट्ठी में इसकी दूसरी ही व्याख्या की है. उनका मानना है कि के.एन. मोदी को बिना उनकी अनुमति के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जा सकता. जाहिर है कि ये संस्थाएं मोदी घराने के प्रति कड़ा रुख अपना रही हैं. लेकिन सही स्थिति का अंदाज अक्तूबर में होने वाली शेयरहोल्डरों की बैठक में ही लग पाएगा.

टिमटिमाएंगे लाइटर

बड़ी सिगरेट कंपनी आईटीसी अपनी वितरण प्रणाली के जरिये एक साल में कम कीमत के दस लाख लाइटर बेचने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है. कंपनी को यह प्रस्ताव मद्रास के एक छोटे उद्यमी ने दिया था. इस बीच ब्रिटेन की रोनसंस दिल्ली के एक अज्ञात उद्यमी से सालाना दस लाख से अधिक लाइटर बनवाने की बातचीत चला रही है. अगर ये योजनाएं सिरे चढ़ीं तो भारतीय सिगरेट लाइटर बाजार में नई टिमटिमाहट जरूर आएगी.

दबाव की रणनीति

सरकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और सैमटेल इंडिया सरीखे प्राइवेट टीवी पिक्चर ट्यूब निर्माताओं ने सिर जोड़ लिए हैं और एक निजी उद्यमी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है. वे उस पर ट्यूबों की कीमत घटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं. हाल ही में उत्तर भारत के एक निर्माता ने 14 इंच की ब्लैक ऐंड व्हाइट टीवी ट्यूब के दाम में 100 रु. की वृद्धि कर दी. इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमटेल इंडिया और क्वालिट्रॉन जैसे ट्यूब निर्माताओं ने निर्यात कम करने और अगले चार महीनों तक हर माह 40,000 ट्यूब देशी बाजार में लाने का फैसला किया है. तब तक उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाने की उम्मीद है. ये कंपनियां देशी बाजार में ट्यूबों की भरमार करके उत्तर भारत की कंपनी को कीमतें घटाने पर मजबूर करने की उम्मीद कर रही हैं.

इटली की सहयोगी

इटली की सरकारी कंपनी स्नैम प्रोगेती एसपीए पहली बार एक भारतीय खाद कंपनी के शेयर खरीदेगी. स्नैम प्रोगेती ने बहुत-सी भारतीय खाद कंपनियों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के समझौते कर रखे हैं पर अब वह के.वी.के. राजू की नागार्जुन फर्टिलाइजर्स ऐंड केमिकल्स के साथ एक दूसरा समझौता करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत वह हैदराबाद की इस कंपनी के 127 करोड़ रु. में से करीब 10 फीसदी शेयर खरीदेगी. यह निवेश नागार्जुन समूह के अनुरोध पर किया जा रहा है जो 635 करोड़ की यूरिया परियोजना में इटली की कंपनी के सहयोग को पक्का करना चाहता है. लेकिन सौदे के लिए वित्त मंत्रालय की अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है.

मोटर साइकिल दौड़

भारी स्पर्द्धा वाले दुपहिया वाहन बाजार में 100 सीसी की मोटरसाइकिलों में जबरदस्त होड़ लग गई है. जापान की कावासाकी के सहयोग से बनी बजाज ऑटो की 100 सीसी मोटरसाइकिलें और एस्कार्ट्स की यामाहा अपने प्रतिद्वंद्वियों को तगड़ी चुनौती देने लगी हैं. हीरो होंडा और टीवीएस-सुजुकी अभी एस्कार्ट्स की यामाहा और बजाज की मोटरसाइकिल से आगे हैं.

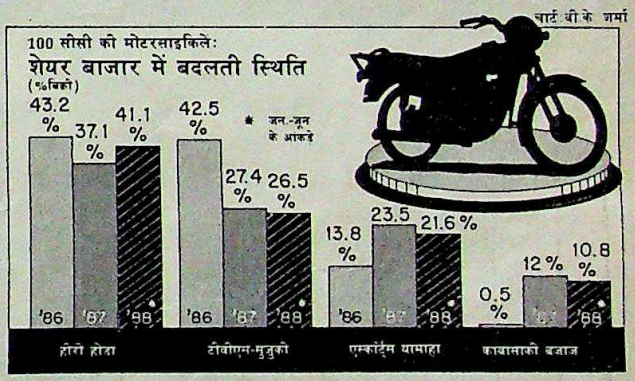

चार्ट: बी.के. शर्मा

पर एस्कार्ट्स और बजाज ने इस अंतर को बहुत कम कर दिया है. उन्होंने हीरो होंडा और टीवीएस-सुजुकी की बिक्री में भी सेंध लगाई है. 1986 में दो फीसदी बाजार पर छायी बजाज की 100 सीसी वाली मोटरसाइकिलों ने 1988 के मध्य तक पहुंचते-पहुंचते 10.8 फीसदी बाजार पर कब्जा जमा लिया. इसी तरह एस्कार्ट्स ने भी 100 सीसी बाजार में 1986 के अपने 13.8 फीसदी के हिस्से को बढ़ाकर इस साल के पहले छह महीनों में 21.6 फीसदी पर पहुंचा दिया (देखें चार्ट).

सोया में फिर उफान

सोया की तेजी बरकरार है. इसके उत्पाद बनाने की पहल गोदरेज सरीखी कंपनियों ने की थी. उसने सोया पेय बनाने की एक अलग कंपनी खोल दी. यह पेय बाजार में तेजी से अपनी जगह नहीं बना पाया. पर अब हालात बदलने लगे हैं और कंपनियां सोया उत्पादों में रुचि लेने लगी हैं. इनमें सबसे आगे खाद्य संसाधन की बड़ी कंपनी फूड स्पेशलिटीज लि. हो सकती है. यह कंपनी सोया से कई वस्तुओं का उत्पादन करेगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कंपनियों की खरीद

पुराने खेल में नया जोश

अब छोटी कंपनियों पर दांव लगने लगे, नए खिलाड़ी भी मैदान में

व्यवसाय जगत में आजकल यह सबसे पसंदीदा खेल है. छोटी कंपनियां एक से दूसरे हाथ में जा रही हैं. कुछ तो चली भी गई हैं और कुछ कंपनियों के प्रबंधक सामने वाले की चाल पीटने के लिए बाहरी मदद भी ले रहे हैं. अहम बात यह भी है कि इस खेल में कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं.

यह खेल है कब्जा जमाने का. कंपनियों पर कब्जा करने के इच्छुक कुछ नामी कंपनियों पर दावा कर रहे हैं. इनमें बेस्ट ऐंड क्राम्प्टन, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, लार्सन ऐंड टुब्रो, शालीमार पेंट्स, कोरामंडल फर्टिलाइजर्स और शायद गॅमोन इंडिया भी शामिल है. उद्योग जगत के कम-से-कम दो बड़े घराने इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड (आईईएल) पर भी नजर गड़ाए हुए हैं.

अब 'खरीदारों' की नजरें सिर्फ बड़ी कंपनियों पर ही नहीं हैं. हाल में कई छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियां या तो खरीद ली गई हैं या बस बिकने ही वाली हैं. इनमें प्रीसिजन फास्टनर्स, कई जूट मिलें, अलिद, सीबीएस टेप्स, पैन टेप्स और नाइसर सिरामिक्स शामिल हैं. कई महत्वाकांक्षी व्यापारी तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में उतरना चाहते हैं.

खरीद की चर्चा चाहे जिस कंपनी की हो, आर्थिक अखबार तुरंत छाबरिया बंधु, रामप्रसाद गोयनका और हिंदुजा बंधुओं जैसे चर्चित और लगातार कंपनियां खरीदते जाने वालों के नाम उससे जोड़ देते हैं. कुछ खबरें तो महज अटकलबाजी ही लगती हैं. टेलेक्स पर लंदन भेजे गए सवालों के जवाब में गोपीचंद हिंदुजा ने इन खबरों का खंडन किया कि उनका समूह केरल स्थित एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कलकत्ता स्थित इंडियन एल्यूमिनियम में कनाडा के एल्यूमिनियम दिग्गज एल्कन के 39.9 फीसदी शेयर खरीदने की कोशिश कर रहा है. हिंदुजा की शिकायत है, "अनेक कंपनियों की खरीद से हमारा नाम जोड़ने वाली कई खबरें आई हैं. पर इससे भी बुरी बात उन रिपोर्टों में दी गई यह सफाई होती है कि हमें ये कंपनियां (जिनके लिए हमने कभी कोशिश ही नहीं की) क्यों नहीं मिल पाई."

लेकिन धुंआ उठ रहा है तो कहीं-न-कहीं आग भी होनी चाहिए. छाबरिया बंधुओं ने 18 करोड़ रु. कारोबार वाली प्रीसिजन फास्टनर्स कंपनी को करीब-करीब खरीद ही लिया है. शॉ वैलेस के प्रबंध निदेशक किशोर छाबरिया भी मानते हैं, "यह सौदा अब पक्का होने ही वाला है." रामप्रसाद गोयनका दो ब्रिटिश कंपनियों, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (आईसीआई) और इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड से उनकी सहायक भारतीय कंपनियों, आईईएल और इंटरनेशनल कंप्यूटर्स इंडियन मैन्यूफैक्चर लिमिटेड (आईसीआईएम) की खरीद के संबंध में बातचीत कर आए हैं.

515 करोड़ रु. कारोबार वाली आईईएल के लिए आदित्य बिड़ला भी प्रयास कर रहे हैं. विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने पिछले दो वर्षों में दो बार आईसीआई से संपर्क करके उसकी भारतीय सहयोगी कपनी आईईएल के प्रबंध में भागीदार बनने या उसके विदेशी शेयर खरीदने की पेशकश की है. अभी सफलता नहीं मिली है.

फिर कई सौदे तो हुए भी हैं: महिंद्रा बंधुओं ने ऑल्विन निसान, नुस्ली वाडिया ने एबॉट लेबोरेटरीज तथा ब्लोप्लास्ट वाले अजय पीरामल ने निकोलस लेबोरेटरीज को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

ऐसी और खरीद की पूरी संभावनाएं हैं. शेयर बाजार से लार्सन ऐंड टुब्रो के शेयर लगातार उठाए जा रहे हैं. पिछले कुछ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महीनों में इसके 20 लाख से अधिक शेयरों की खरीद की जा चुकी है. जुलाई और अगस्त के शुरू में ही इसकी कीमतों में 30 फीसदी की वृद्धि हो गई और प्रति शेयर 122 रु. का हो गया. 580 करोड़ रु. कारोबार वाली इस इंजीनियरिंग कंपनी के प्रभावित खरीदारों के रूप में दो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं: दुबई के व्यापारी मनोहर छाबरिया और रिलायंस के धीरूभाई अंबानी. दोनों ही इसका खंडन करते हैं.

शालीमार पेंट्स में लगे ब्रिटिश कंपनी इंटरलक्स के 40 फीसदी शेयर हासिल करने के लिए भी भागदौड़ चल रही है. एक मर्चेंट बैंकर के अनुसार कम-से-कम 15 लोग इन शेयरों के लिए दावेदार हैं.

कंपनियों पर कब्जा करने के इस दौर में नए चेहरे सामने आए हैं. बंबई में प्रबंधन के कारोबार में लगे आर.वी. पंडित, लुधियाना के अभय ओसवाल और कलकत्ता के जूट का कारोबार करने वाले अरुण बजोरिया ऐसे ही लोग हैं. पंडित ने टाटा समूह से सीबीएस टेप्स और बंगलूर का पैन टेल खरीद लिया है. ओसवाल यूनियन कार्बाइड से बंबई के चेंबूर स्थित उसके एलडीपीई प्लांट तथा डीसीएम से राजस्थान के कोटा में स्थित उसके खाद कारखाने को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं.

बजोरिया ने जिस तेजी से कंपनियों पर कब्जा किया है उससे वे भी चर्चा में आ गए हैं. बहुत जल्दी-जल्दी उन्होंने मैकलियड समूह की वेवरली, जे.डी कोठारी की गांडालपाड़ा, गौरीप्रसाद गोयनका की जगतदल, बांगड़ समूह की फोर्ट ग्लोस्टर तथा जी.पी. बिड़ला की हुकुमचंद जूट मिल खरीद ली है. इस खरीद के बाद वे अब देश के कुल जूट उत्पादन में 15 फीसदी के भागीदार बन गए हैं. इससे भी बड़ी बात है कि इस खरीद के लिए उन्होंने बैंकों से कर्ज लेने की जगह अपने घर का पैसा ही लगाया.

कंपनियों की खरीद के प्रति बड़ा आकर्षण कई बार उनकी कम कीमत के कारण भी होता है. बजोरिया बताते हैं, "80 टन उत्पादन वाली नई जूट मिल लगाने में 50 करोड़ रु. से अधिक रकम खर्च होती है. मैं ऐसी मिलें मात्र ढाई-ढाई करोड़ रु. में हासिल कर रहा हूं. इसलिए मैं इनकी खरीद क्यों न करूं?" इनमें से अधिकांश मिलें घाटा दे रही हैं लेकिन बजोरिया ने उनकी सिर्फ मशीनें और दूसरी संपत्ति खरीदी है और मजदूरों तथा ग्रेच्यूटी संबंधी देनदारियों का भार स्वीकार किया है.

व्यापारी उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी नजर गड़ाए रखते हैं जो भारत से अपना कारोबार समेटना चाहती हैं. भारत की सहयोगी कंपनी से रिश्ता तोड़ने की इच्छुक विदेशी कंपनियों पर भी उनकी निगाह रहती है. इस खेल के कई खिलाड़ी नकदी पूंजी के मामले में समृद्ध कंपनियों की ओर भी आकर्षित होते हैं क्योंकि इन कंपनियों की पूंजी बाद में दूसरी कंपनियों को खरीदने के काम आती है. किशोर छाबरिया कहते हैं कि वे तीन मापदंडों पर कंपनियां खरीदने को प्रेरित होते हैं: अच्छा प्रबंध, उपभोक्ता उत्पादन और अच्छा मुनाफा.

मद्रास की ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष उद्योगपति एम.वी. अरुणाचलम का कहना है कि सरकार चूंकि बीमार कंपनियां अपने हाथ नहीं ले रही है और स्वस्थ कंपनियों में उनके विलय को प्रोत्साहित कर रही है इसीलिए यह प्रवृत्ति बढ़ रही है. उनका कहना ठीक है. इस नीतिगत बदलाव से कंपनियों की 'दोस्ताना' खरीद शुरू हुई है. हाल में ही 13 करोड़ रु. कारोबार वाली नाइसर सिरामिक्स का विलय 30 करोड़ रु. कारोबार वाली स्पार्टेक सिरामिक (इंडिया) में हो गया. स्पार्टेक ने नाइसर कंपनी शुरू करने वाले और शेषशायी समूह के प्रमुख एस. विश्वनाथन से 40 फीसदी शेयर खरीद लिए.

इस बात में संदेह नहीं कि केंद्र की चुप्पी के कारण ही कंपनियों की खरीद का यह दौर शुरू हुआ है. सरकार मानती है कि यह कंपनियों का आपसी मसला है. वित्तीय संस्थाओं के साथ ऐसा मामला नहीं है. मध्यम और बड़ी कंपनियों में 15 से लेकर 40 फीसदी शेयर रखने वाली इन संस्थाओं की भूमिका कंपनियों की खरीद-फरोख्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है.

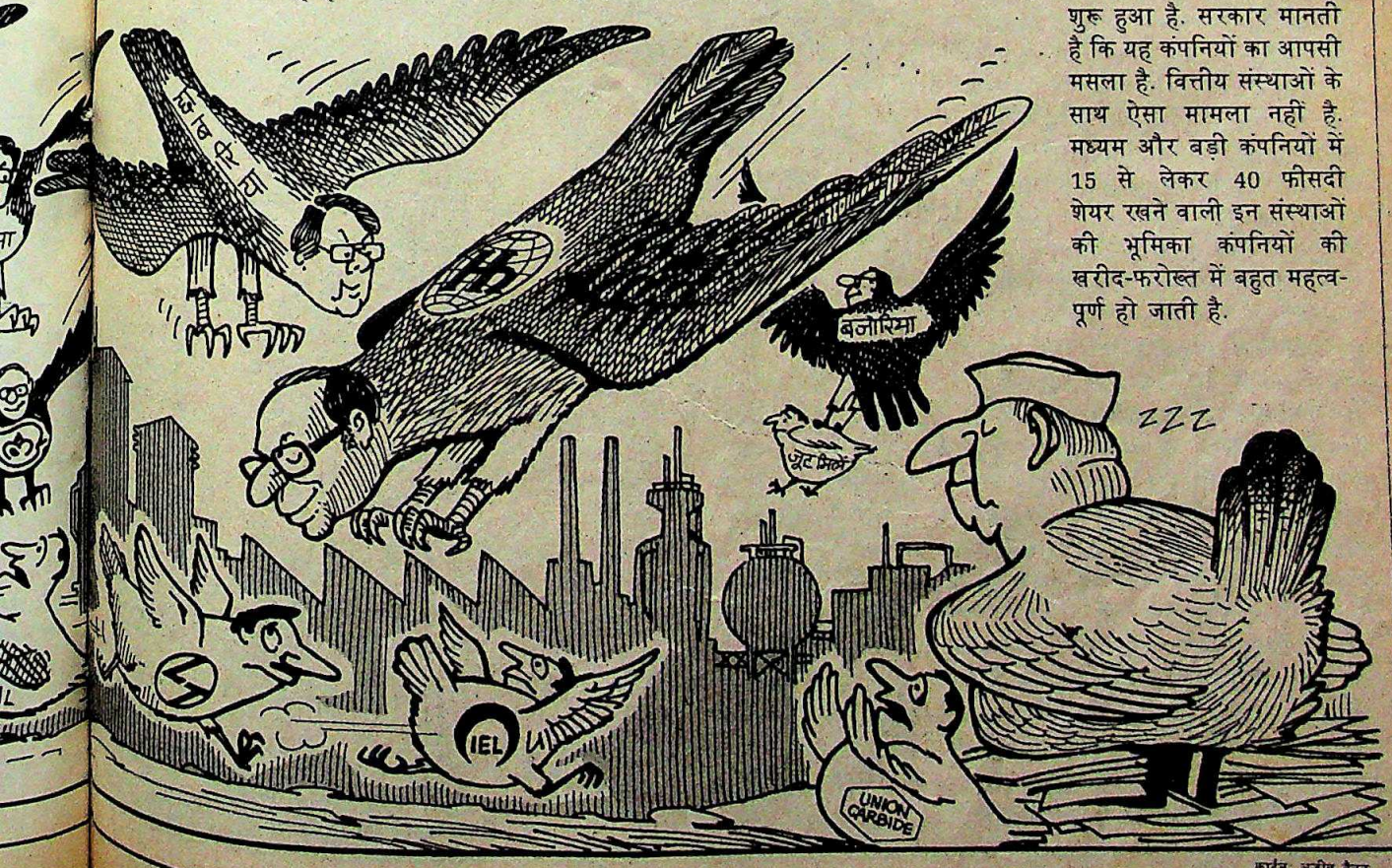

कार्टून: अजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बहरहाल, व्यापारी वर्ग अपने को इस नए वातावरण का अभ्यस्त बनाने लगा है. कई ने कब्जा जमाने वालों की निगाह पड़ते ही बचाव की तैयारियां शुरू कर दीं. जैसे इंडियन टुबैको कंपनी ने कलकत्ता की त्रिवेणी टिश्यूज के 51 फीसदी विदेशी शेयर अपनी मूल विदेशी कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टुबैको कंपनी को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कंपनी के अध्यक्ष जे.एन. सप्रू कहते हैं, "यह कंपनी पर कब्जा जमाने की नहीं, दूसरे का कब्जा रोकने की कार्रवाई थी." आईटीसी सिगरेट निर्माण के लिए इसी कंपनी का कागज उपयोग करती है. उसे लग रहा था कि इस कंपनी पर छाबरिया, पोद्दार घराने और एक आप्रवासी भारतीय की नजर है.

कुछ हफ्ते पहले जब ईआईडी पैरी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन.वी. सुबैय्या को इस बात की भनक लगी कि कोई अज्ञात खरीदार कोरामंडल फर्टिलाइजर्स के शेयर उठाने लगा है तो उन्होंने वित्तीय संस्थाओं के पास पड़े कंपनी के शेयर खरीद लिए. पैरी का कोरामंडल से व्यापारिक रिश्ता है और सुबैय्या इसकी हिफाजत चाहते थे. किसी बाहरी आदमी के आ जाने से यह संबंध गड़बड़ा जाता. इसीलिए पैरी ने 180 करोड़ रु. कारोबार वाली इस कंपनी में अपने शेयर 8 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिए.

कंपनियों की खरीद-फरोख्त के इस दौर में कुछ 'बाहरी मददगारों' का आ जाना भी महत्वपूर्ण है. ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? एक राय यह है कि अंबानी ऐसे आदमी हैं. नरोत्तम (निक्की) मंगलदास देसाई दस साल से लार्सन ऐंड टुब्रो के अध्यक्ष हैं. इधर लग रहा था कि मार्च 1989 में वे अपने पद से हट जाएंगे तभी छाबरिया ने कंपनी के 1.5 फीसदी शेयर खरीद लिए. देसाई के अलावा कोई और नहीं जानता कि इसके बाद क्या हुआ. और वे खुद कुछ नहीं बता रहे हैं. लेकिन देसाई मदद के लिए अपने पूर्व परिचित अंबानी की मदद मांग सकते थे और वे कंपनी के शेयर खरीदकर इस पर किसी संभावित कब्जे को रोक सकते थे.

इस कहानी की पुष्टि नहीं हो सकती. लेकिन अगर कोई सरकारी एजेंसी इस काम में लगे तो कंपनियों की खरीद संबंधी दूसरे किस्से भी उजागर हो जाएंगे. नवगठित भारतीय शेयर बाजार परिषद कंपनियों की खरीद संबंधी नियम तय करना चाहती है. इससे कुछ कानूनी बदलाव तो जरूर होगा लेकिन कंपनियों की खरीद करने वाले लोगों का उत्साह कम नहीं होगा.

—आनंद पी. रमन, एम. रहमान, एस.एच. वेंकटरमनी
ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

कार्यपद्धति

दबे पांव आता हुआ बदलाव

जापानी औद्योगिक संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता

भोर में 6.15 पर कारखाने के भीतर से कुछ अटपटी-सी आवाजें आने लगती हैं. इसके बाद वहां जो कुछ होता है वैसा दृश्य तो कारखानों में आम तौर पर दिखाई नहीं देता. 20 मजदूरों के सामने खड़ा एक दुबला-पतला नौजवान सुपरवाइजर अपने हाथ पहले सिर के ऊपर ले जाता है, फिर नीचे करता है, उनसे अंगूठे छूता है, शरीर को बाईं ओर झुकाता है, फिर दाईं ओर. सभी मजदूर उसका अनुकरण करते जाते हैं. 15 मिनट तक वह उन लोगों से इसी तरह की कसरत करवाता है. फिर वे सभी मजदूर अपने-अपने काम पर चल देते हैं.

आइए कुछ किलोमीटर दूर बनी दूसरी कंपनी में चलें. यहां सुबह 7.35 पर मजदूर अपने फोरमैन के पास जुटे हैं और दिन के उत्पादन के लक्ष्य और कल की गड़बड़ी के बारे में बात कर रहे हैं. यह बातचीत दसेक मिनट ही चलती है. लेकिन हर रोज होती है.

क्या ये कंपनियां और उनके ये किस्से जापान के हैं? नहीं, ये कंपनियां हैं हीरो होंडा और मारुति उद्योग, जो दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं.

यूकोसो—यह दिन के काम का श्रीगणेश करने की जापानी शैली है. अब यह शैली अपनाने वाली भारतीय कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है. दरअसल यह व्यायाम और 'टूल बॉक्स' मीटिंग उस क्रांति की एक झलक भर हैं जिसका सूत्रपात आज भारतीय प्रबंध जगत में भी हो रहा है.

अपनी जापानी सहयोगी कंपनियों की देखा-देखी एस्कॉर्ट्स, हीरो होंडा, मारुति उद्योग और उसकी अनेक सहायक इकाइयां, स्वराज माजदा, आइशर मोटर्स और बडोदरा की एक बैटरी कंपनी भी कामकाज का जापानी तरीका अपनाने लगी हैं. ऐसे तरीकों में शामिल हैं:

- मजदूरों और प्रबंधकों के लिए एक ही कैंटीन और एक ही रंग की पोशाक. हीरो होंडा में सफेद रंग की वर्दी है, मारुति में भूरी और दिल्ली से 94 किमी दूर स्थित मारुति की सहयोगी कंपनी असाही इंडिया सेफ्टी ग्लास में नीली.
- बिना केबिन या दीवारों वाले दफ्तर.

अपनी जापानी सहयोगी कंपनियों की देखा-देखी एस्कॉर्ट्स, हीरो होंडा और मारुति उद्योग और उनकी अनेक सहायक इकाइयां कामकाज का जापानी तरीका अपनाने लगी हैं

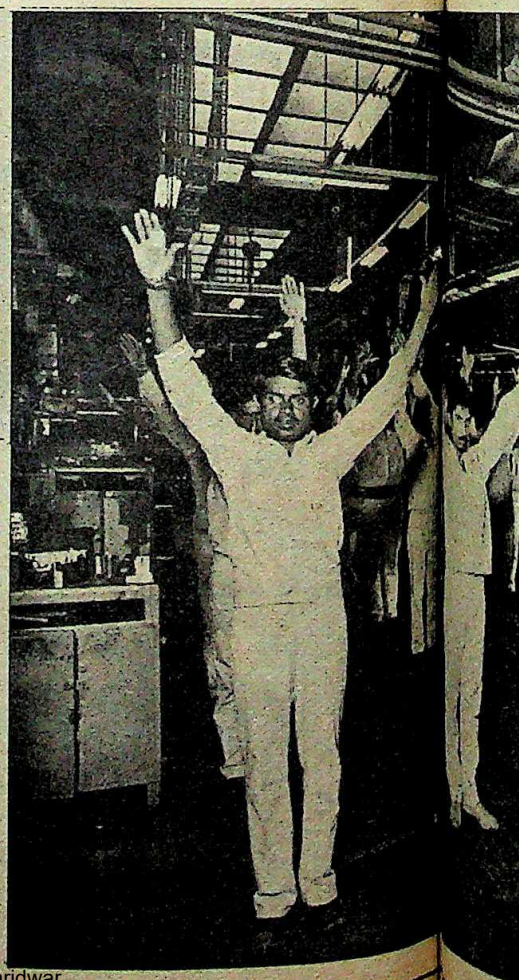

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो प्रशांत पंजियार

जैसे पंजाब के रोपड़ में स्थित स्वराज माजदा के विशाल कारखाने में सिर्फ एक ही केबिन बना है (वह भी सबसे बड़े अधिकारी के लिए). बाकी सभी बड़े अधिकारी खुले हॉल में ही बैठते हैं.

▸ कारखाने में सुपरवाइजरों और मजदूरों की प्रतिदिन बैठक. आइशर गुडअर्थ के अध्यक्ष विक्रम लाल बताते हैं, "हमारे कारखाने में रोज एक बार सुपरवाइजर, इंजीनियर और मजदूर बैठकर उत्पादन से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करते हैं."

▸ सर्वसम्मति से फैसला. हीरो होंडा के प्रबंध निदेशक रमनकांत मुंजाल कहते हैं, "हीरो होंडा में एक बार फैसला हो जाने पर सभी उसे मानते हैं."

▸ रोज काम के बाद काम करने की जगह की सफाई खुद करना. अनेक कारखानों में इस

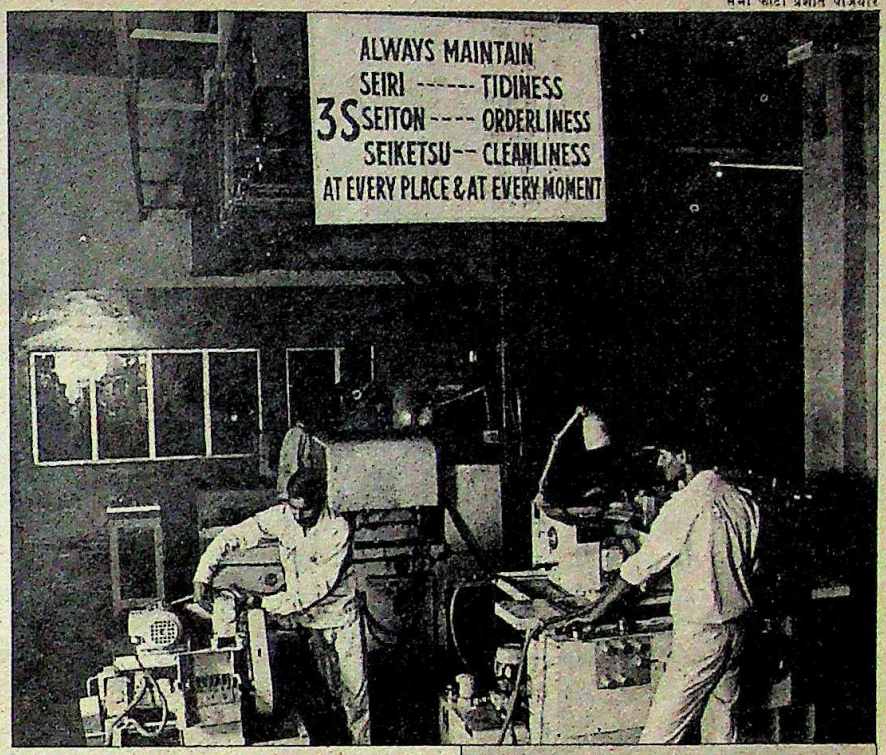

▸ (दाएं) कर्मचारियों के लिए निर्देश: बदलता नजरिया

▸ हीरो होंडा की वर्कशाप में व्यायाम करते मजदूर: नया जोश

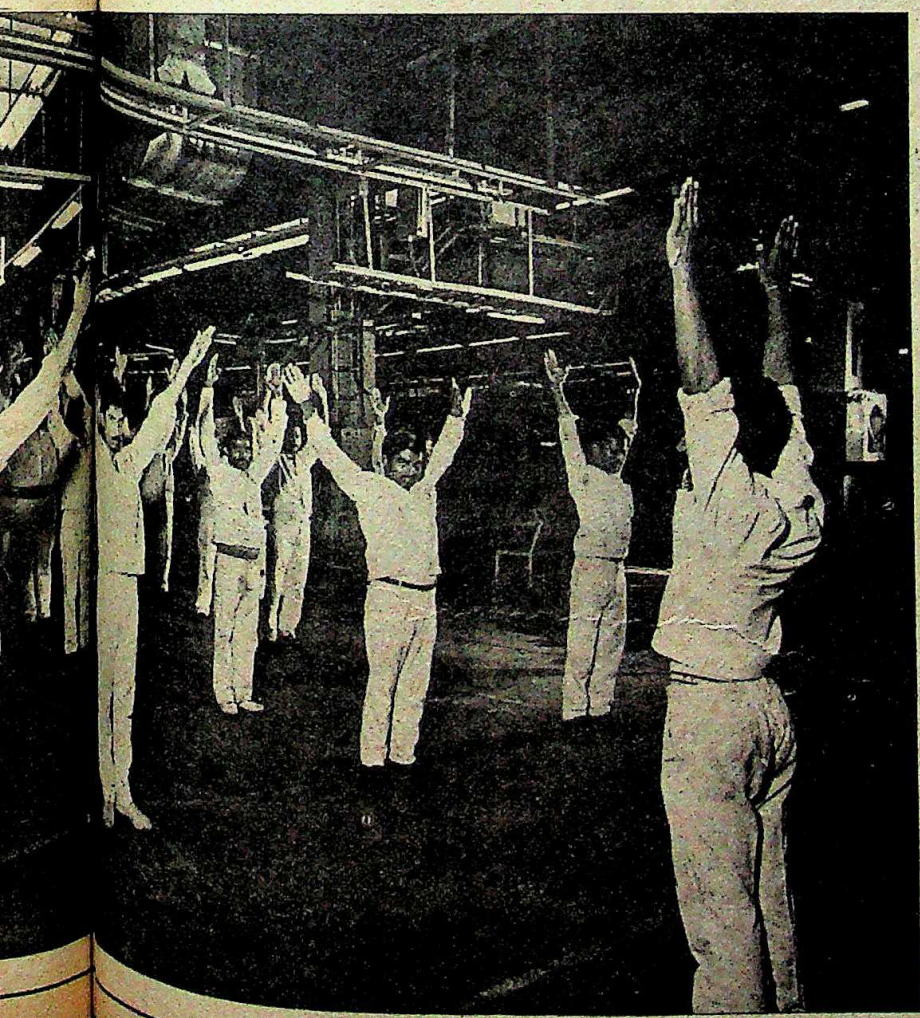

एक ही कैंटीन और एक जैसी पोशाक बराबरी का भाव पैदा करती है. यह इस बात का प्रतीक है कि सब लोग कंपनी की एक ही टीम के सदस्य हैं. कोई छोटा-बड़ा नहीं

काम के लिए जमादार रखे ही नहीं गए हैं. कारखानों में 'सेइरि', 'सेइतान' और 'सेइकुत्सु' यानी सुव्यवस्थितता, नियमितता और स्वच्छता बरतने के दिशानिर्देश हर जगह प्रमुखता से लगे हुए हैं.

▸ माल का स्टॉक कम रखना. जापानी इसे 'कनबन' यानी तुरत-फुरत वाली व्यवस्था कहते हैं. आपूर्तिकर्ता मारुति को कुछ पुर्जे रोज सप्लाई करते हैं. मारुति के एक अधिकारी बताते हैं, "कार सीट, बंपर और स्टियरिंग सिस्टम जैसी चीजों का हमारा स्टॉक तो सिर्फ दो घंटे की जरूरतों तक का ही रहता है. हां, नट-बोल्ट का स्टॉक दो महीने तक जा सकता है. (ऑटोमोबाइल उद्योग में आम तौर पर तीन हफ्ते से लेकर तीन महीने तक का स्टॉक रखा जाता है) और इस प्रकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निर्माता स्टॉक सीमित करके करोड़ों रु. बचा सकते हैं.

► समस्याओं पर बातचीत. समय-समय पर होने वाली इन बैठकों में मजदूर अपनी व्यावहारिक समस्याएं रखते हैं जिनको निबटाया जाता है.

जो कंपनियां इन तरीकों को लागू कर रही हैं, वे नई हैं और उनके यहां आने वाले कर्मचारी भी सीधे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निकलकर आते हैं.

ये सभी तरीके बहुत व्यावहारिक हैं. एक ही कैंटीन और एक तरह की पोशाक समता का भाव पैदा करती है. यह इस बात का प्रतीक है कि कंपनी के लोग एक ही टीम के सदस्य हैं.

लेकिन इनमें से कुछ तरीके तो भारत में पहले से आजमाए जा रहे हैं. मजदूरों की समस्याएं निबटाने वाली बैठकें मोदी रबर और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान 'भेल' में अरसे से चल रही हैं. टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी सैमटेल में भी खुले दफ्तर थे. टीवीएस-सुजुकी के प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन कहते हैं कि जापानी कंपनी से गठबंधन करने से काफी पहले से ही उनके यहां एक ही कैंटीन और एक रंग की वर्दी चल रही थी.

फिर भी इस बात में संदेह नहीं कि पिछले पांच वर्षों में जापानी कंपनियों से गठबंधन का सिलसिला चल पड़ने के बाद से ही ये तरीके बड़े पैमाने पर अपनाए जाने लगे. जापान की मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल्स से गठबंधन करने के बाद सैमटेल ने इन बैठकों में मजदूरों को बताया कि वे अपनी समस्याओं का विश्लेषण किस तरह से करें. कंपनी के प्रबंध निदेशक सतीश कौड़ा बताते हैं, "अब यह काम काफी जोर-शोर से होता है. हम लोग एक शामियाना लगवाते हैं जिसमें मंच भी बना होता है. ऐसी बैठकों में तीन महीने तक एक योजना पर बातचीत होती है और परिणाम चार्टों के माध्यम से दिखाए जाते हैं."

फिर भी टीवीएस के श्रीनिवासन की इस बात में दम है कि एक जैसी वर्दी और एक कैंटीन बना देने भर से ही काम की जापानी संस्कृति नहीं आ जाती. उनकी बात से जापानी अधिकारी भी सहमत हैं. हीरो होंडा के प्रबंधक मंडल में जापानी होंडा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वाई. साइतो कहते हैं, "जापानी प्रबंध में व्यायाम, एक कैंटीन और वर्दी ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे का दर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है."

इसी दर्शन के कई भक्त हैं. मारुति उद्योग और सेल के अध्यक्ष वी. कृष्णमूर्ति समानता, उत्पादन लक्ष्य और क्वालिटी के प्रति मजदूर

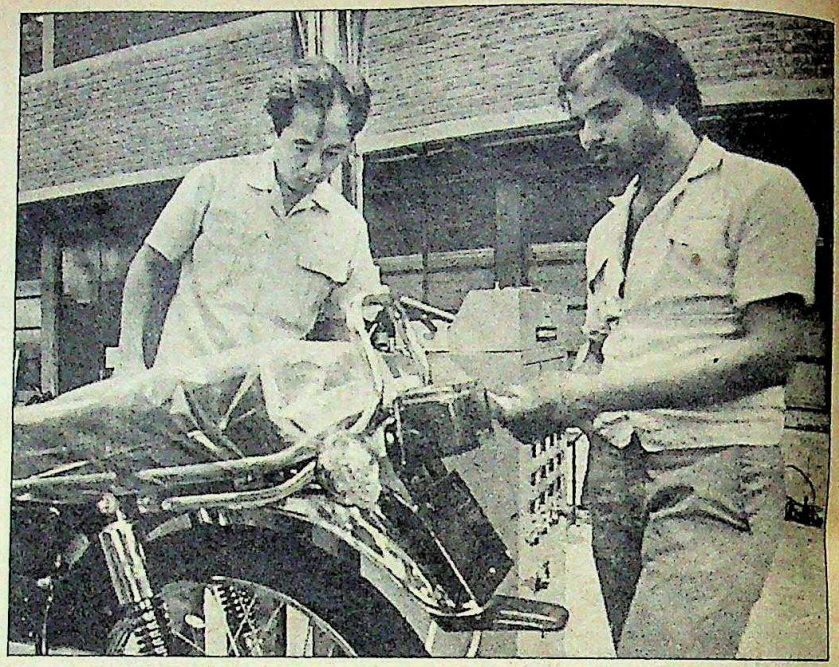

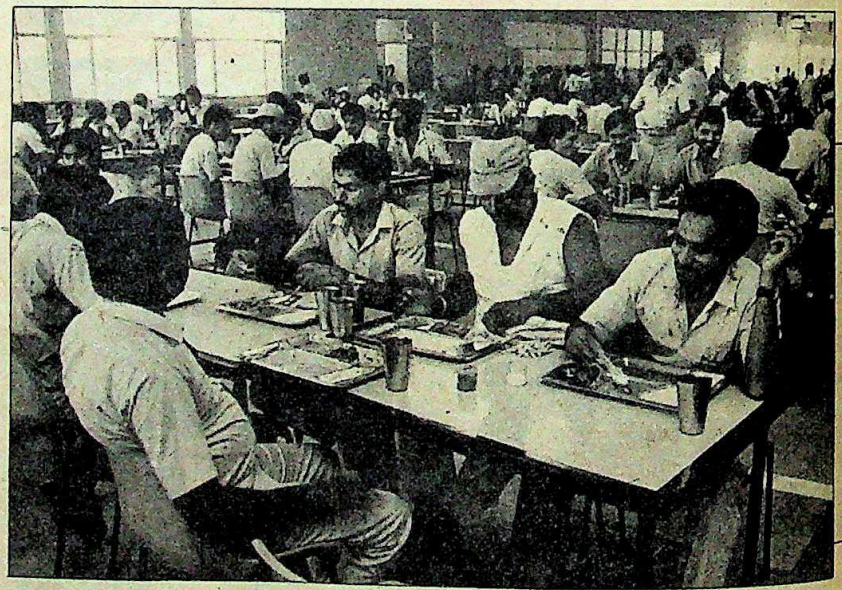

■ (ऊपर) यामाहा के प्रतिनिधि एरिमा एस्कॉर्ट्स कारखाने में

■ मारुति उद्योग की कैंटीनः बराबरी की संस्कृति

की निष्ठा की जापानी विशेषता की बात करते हैं. वे कहते हैं, "हर जापानी अपने दफ्तर को घर का ही एक अंग मानता है, उससे अलग नहीं. वहां मूल्यों का आदर और अपनी संस्था के प्रति निष्ठा का बहुत महत्व है. यह बात भारत में नहीं है."

किसी संगठन में मिलजुलकर काम करना और वहां समता का भाव होना सफलता का मूल मंत्र हैं. मारुति के प्रबंध निदेशक आर.सी. भार्गव कहते हैं, "जापानी प्रबंध की बुनियादी ताकत उस सोच में है जिसके तहत वे मानव संसाधन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं."

इस बात में संदेह नहीं कि व्यक्ति के प्रति चिंता से ही उत्पादन का ऊंचा लक्ष्य और संगठन की उत्पादकता जुड़ी हुई है. जापानी प्रबंध को इन चार प्रमुख कसौटियों पर कसा जा सकता है: उत्पादकता, कर्मचारियों की अनुपस्थिति और कंपनी छोड़ने की दर तथा श्रमिक असंतोष का स्तर. मुश्किल यह है कि कोई भी भारतीय कंपनी जापानी प्रणाली अपनाने से हो रहे फायदे का समुचित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

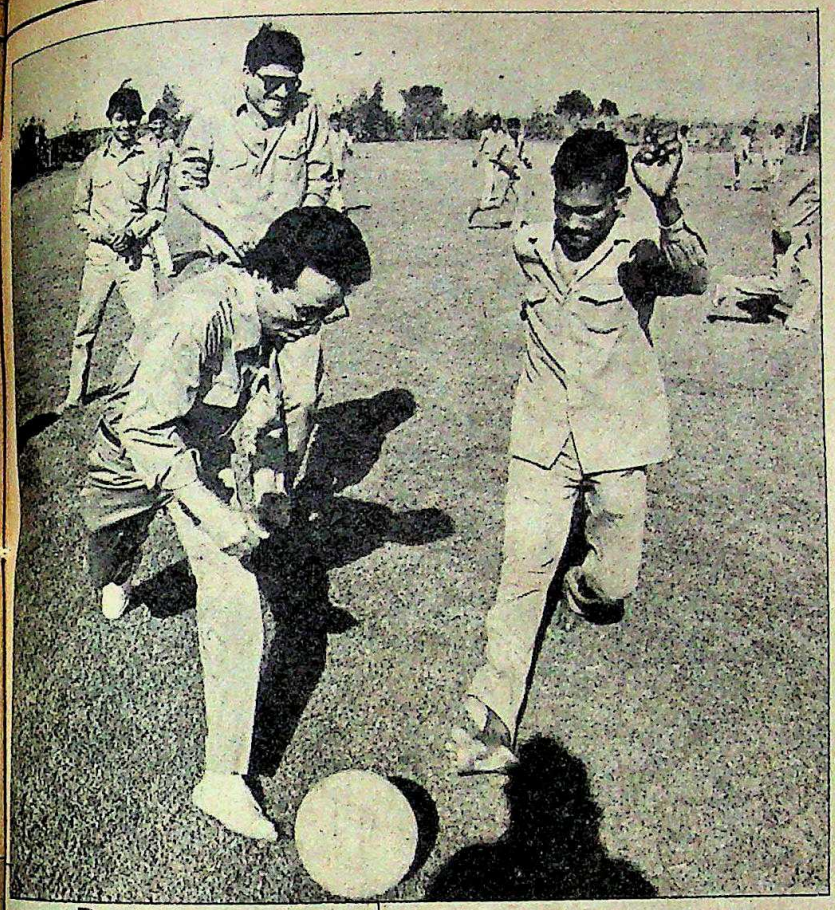

■ असाही सेफ्टी ग्लास कंपनी के अधिकारी और मजदूरः साझा खेल

ऐसा नहीं कि इस बदलाव में झमेले नहीं हैं. जापानी रंग-ढंग से चलने वाली कंपनियों के कई कर्मचारी काम छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं

मूल्यांकन नहीं कर रही है. हीरो होंडा के महाप्रबंधक अमित चतुर्वेदी मानते हैं, "जो कंपनियां इन तरीकों पर अमल नहीं कर रही हैं, उनके साथ कामकाज की कोई तुलना ही नहीं की गई है."

इसके बावजूद ऐसे कुछ प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि इन कदमों से कंपनी के मनोबल पर अच्छा असर हुआ है. लेकिन इससे कुछ झमेले भी पैदा हुए हैं. जो कंपनियां अपने कर्मचारियों से बहुत सम्माननीय व्यवहार करती हैं उनके कम ही कर्मचारी वहां से काम छोड़कर कहीं और जाते हैं. लेकिन जापानी रंग-ढंग अपनाने वाली अनेक कंपनियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है. मारुति कंपनी जब बनी थी तब इसमें काम शुरू करने वाले कई लोग, जिनमें महाप्रबंधक और उप-महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी भी हैं, कंपनी छोड़कर चले गए. ऐसा ही दूसरी कंपनियों के साथ हुआ है. मारुति और हीरो होंडा को तो गंभीर श्रमिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा.

यही नहीं, समता की बात चाहे जितनी कर ली जाए, भारतीय प्रबंधक मजदूरों के साथ एक ही कैंटीन में बैठने से हिचकते हैं. मारुति उद्योग मजदूर संघ के महासचिव मैथ्यू अब्राहम कहते हैं, "कैंटीन में सभी मैनेजर एक साथ लेकिन हमसे अलग ही बैठते हैं." हीरो होंडा के एक अधिकारी भी निजी बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं, "अक्सर मैं खाली मेज ही तलाशता हूं."

व्यावहारिक समस्याएं दूर करने वाली बैठकों में मजदूर खुद भी खर्च बचाने तथा उत्पादन संबंधी मुश्किलें दूर करने वाले कई सुझाव देते हैं. मारुति के भार्गव कहते हैं कि मजदूरों की कुशलता उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझावों और उन्हें लागू करने के आधार पर ही मापनी होगी. इस मामले में यह कार कंपनी बहुत सफल साबित हुई है. लेकिन इसकी वजह यह है कि वहां मजदूरों को प्रति सुझाव दो रु. तथा सुझाव लागू होने से होने वाली बचत की दो फीसदी राशि दी जाती है.

फिर यह मुद्दा महत्वपूर्ण है कि जापान में मजदूरों को वार्षिक बोनस के अलावा और कोई फायदा नहीं दिया जाता. मारुति के प्रबंधक मंडल में सुजुकी के प्रतिनिधि एन. हरादा स्वीकार करते हैं, "जापान में मासिक प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती." इसका मतलब हुआ कि भारतीय कंपनियां जापानी तरीके से हट रही हैं. लेकिन यह बुनियादी मुद्दा नहीं है. भारतीय कंपनियों से संबद्ध कुछ जापानी अधिकारी ऐसे कामों से नाराज रहते हैं. हालांकि नाओकी एरिमा इस बात से साफ इनकार करते हैं. एस्कॉर्ट्स के सूरजपुर कारखाने में यामाहा के रेजिडेंट इंजीनियर एरिमा कहते हैं, "मजदूरों से सहयोग पाना और उनका दिल जीतना बहुत मुश्किल काम है. यहां मजदूर सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनसे कहा जाता है."

वर्ग और जाति के आधार पर विभाजित उस समाज में ऐसा होगा ही जहां शिक्षा का स्तर काफी कम है. असाही इंडिया सेफ्टी ग्लास के कार्यकारी उपाध्यक्ष संजय लाबू कहते हैं, "सिर्फ जापानी व्यवस्था लाद देने से ही लाभ नहीं होगा. हमारे यहां जाति और धर्म जैसे अनेक झमेले हैं. इसलिए हमने जापानी व्यवस्था की सबसे अच्छी चीजें ले ली है. हम उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं."

असाही, आइशर और स्वराज माजदा जैसी कंपनियों ने जापानी व्यवस्था में फेर-बदल कर लिए हैं. जैसे असाही के मजदूर रोज व्यायाम नहीं करते. इसकी जगह वे लोग फुटबॉल खेलते हैं. पिछले पखवाड़े यहां हुए एक मैच में मजदूरों के साथ इस कंपनी के मालिक लाबू समेत वहां के बड़े अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया.

पर इस व्यवस्था की असली परीक्षा कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने में ही है. एस्कॉर्ट्स के सहायक उपाध्यक्ष आर.एस. वासदेव कहते हैं, "सवाल यह है कि ये तरीके चलते हैं या टें बोल जाते हैं." लेकिन सुजुकी के हरादा कहते हैं कि अभी और समय दिया जाना चाहिए. वे कहते हैं, "30 साल पहले जापान और अमेरिका में काफी अंतर था. आज यही अंतर भारत और जापान में है. भारत को 30 नहीं तो 5-10 वर्ष तो लगेंगे ही." ऐसा हो सकता है. उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसी दरम्यान भारतीय प्रबंधक जापानी तरीके से सायोनारा (अल-विदा) नहीं कहेंगे.

—पलकुन्नथु जी. मथाई, ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विज्ञापन

बच्चों के जरिये बड़ों तक

विज्ञापन उद्योग छोटों से बड़े फैसले करवाने का इच्छुक

पहले मांएं अपने नन्हे-मुन्नों को मेहमानों के सामने स्कूल में रटाई गई कविताएं सुनाने के लिए कहती थीं. अब बच्चे अपने पसंदीदा विज्ञापनों की पंक्तियां झटपट सुना देते हैं. फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में माताएं बच्चों को रॉबिनहुड या बच्चियों को जापानी गुड़िया की तरह सजाकर भेजती थीं. अब बच्चे ओनिडा के राक्षस और रसना वाली लड़की का रंग-रूप धरने की जिद करते हैं और पुरस्कार भी जीत लाते हैं. पहले इतवार को बच्चे बाहर क्रिकेट या लुका-छिपी खेलने निकलते थे. अब टीवी को घेरे वे इस बात पर बाजी लगाते हैं कि अगला विज्ञापन कौन-सा आएगा. बच्चे अब बच्चे न रहे, वे विभिन्न चीजों के प्रचारक बन गए हैं. वे इन चीजों की खरीद के लिए दबाव भी डालने लगे हैं.

भारतीय विज्ञापन जगत को एकाएक नया दर्शक वर्ग मिल गया है, बच्चों के रूप में. पूरे देश में बिक्री के धंधे से जुड़े लोग और विज्ञापन एजेंसियां टीवी के माध्यम से सीधे बच्चों तक अपनी पहुंच बना रही हैं. वे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने तरकश के सभी तीर इस्तेमाल कर रही हैं—तुकबंदी, स्मृति में गहरे पैठने वाली चीजें या कार्रवाई जैसे, विक्स वाली खिच-खिच, कोलगेट सुरक्षाचक्र और खुद बच्चों को विज्ञापन में उतारना (रसना, मैगी नूडल्स).

प्रचार के ये हथकंडे काफी असरदार साबित हुए हैं. अब कई घरों में बच्चे विज्ञापनों की ये तुकबंदियां गाते दिखते हैं—वाशिंग पाउडर निरमा, विक्स की गोली लो या मैगी. दो मिनट या फिर इन पंक्तियों की नकल करते मिलते हैं. मोगांबो खुश हुआ, पामोलिव दा जवाब नहीं, आइ लव यू रसना. बच्चों के बीच नए बाल कलाकार (जैसे रसना वाली लड़की, न्यूट्रामूल दादा) जबरदस्त लोकप्रिय हो गए हैं.

निश्चित ही विज्ञापन उद्योग को नया लाभदायक क्षेत्र मिला है. कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि नई प्रवृत्ति का कंपनियों की बिक्री पर क्या असर हो रहा है क्योंकि बच्चे विज्ञापनों के लिहाज से महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसके एक पहलू भर हैं. लेकिन दो विज्ञापन एजेंसियां बच्चों की जीवन पद्धति का अध्ययन कर रही हैं जिससे इस अनुमान की दिशा में बढ़ा जा सके. बंबई की पाथ-फाइंडर्स विज्ञापन एजेंसी की नई सहयोगी इनसाइट, 10 महानगरों के 4000 से अधिक बच्चों के सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय बच्चों के 'मनोविज्ञान' का पता कर रही है. बंबई की बाजार अनुसंधान कंपनी 'मार्ग' की सहायक मीडिया सर्च 16 महानगरों और शहरों के 5325 बच्चों की प्रचार माध्यमों संबंधी आदतों का अध्ययन कर रही है.

विज्ञापनों में बच्चों को हरदम प्रमुख स्थान मिलता है, खास तौर पर तब, जब विज्ञापन चॉकलेट, बिस्कुट और खिलौनों के हों. लेकिन विज्ञापन एजेंसियां अब दूसरी चीजों के विज्ञापनों में भी बच्चों की बड़ी

प्रशांत पंजियार

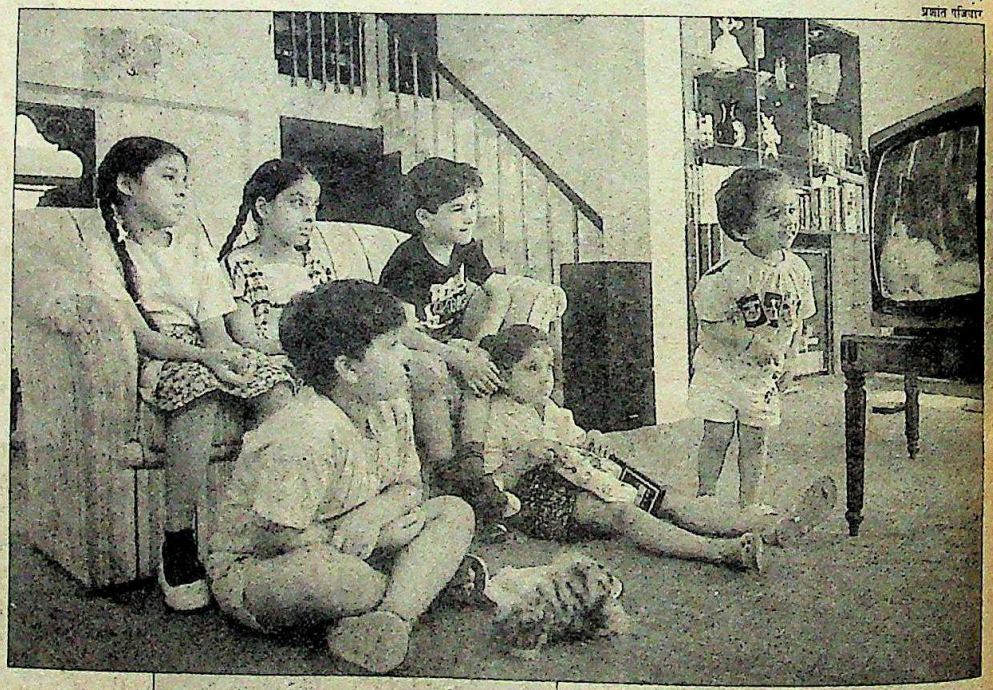

विज्ञापन एजेंसियों के लोगों का मानना है कि बच्चे ही सबसे अधिक समय टीवी देखते हैं और विज्ञापनों को याद रखते हैं. कुछ का कहना है कि दो-तीन वर्ष के बच्चे भी विज्ञापन और कार्यक्रम में फर्क कर लेते हैं

भूमिका रख रही हैं. जैसे, यूरेका फोर्बेस वैक्यूम क्लिनर के विज्ञापन में दिखाया गया कि कंपनी का सेल्समैन जब ग्राहक के घर जाकर खुद सफाई करके दिखाता है तो बच्चा किस तरह खुश हो जाता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने विमल कपड़ों के विज्ञापन में पिछले साल सिर्फ लड़कियों को पेश किया था. अब उसके इन विज्ञापनों में एक बच्चा भी शामिल है.

हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स (एच-टीए) की दिल्ली शाखा के प्रमुख निखिल नेहरू मानते हैं, "आज ऐसे विज्ञापनों की भरमार है. साथ ही विज्ञापनों का स्तर भी बढ़िया है. दिखाने का अंदाज भी निराला है."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनकी बात सही है. अब विज्ञापन अधिक गतिशील, ज्यादा खुशनुमा और अक्सर बच्चों को केंद्र में रखकर बनाए जा रहे हैं.

बच्चों में विज्ञापन एजेंसियों की दिलचस्पी बढ़ने के कई कारण हैं. आम धारणा है कि बच्चे भारतीय परिवार का केंद्र होते हैं और जब खाने के तेल, साबुन या टूथपेस्ट जैसे पारिवारिक सामान का विज्ञापन करना हो तो बच्चों को भुलाया नहीं जा सकता. खाद्य पदार्थ बनाने वाली एचएमएम कंपनी के की महाप्रबंधक अभिजीत बसु कहते हैं, परिवार में खपने वाली किसी भी चीज के विज्ञापन में बच्चा जरूर रहेगा. इस देश के लोग बच्चों से बहुत मोह रखते हैं."

इससे भी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि क्या घर के सामान खरीदने के फैसले को प्रभावित करने की स्थिति में हो सकता है. चीज खरीदने के लिए मां-बाप के पीछे पड़ जाएं. नए उत्पादों के मामले में ऐसी प्रवृत्ति ज्यादा है क्योंकि नई चीजें बच्चों के जरिये घरों में प्रवेश पाती हैं. नई चीजें बच्चों को आकर्षित करती हैं इसलिए इसे जायज तरीका माना जा सकता है.

तीसरे, विज्ञापन एजेंसियों के लोगों का मानना है कि घर में बच्चे ही सबसे ज्यादा टीवी देखते हैं. दिल्ली की विज्ञापन कंपनी तारा सिन्हा एसोसिएट्स के निदेशक पॉल नैय्यर कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई दो राय हो सकती है. बच्चे तो टीवी से चिपके ही रहते हैं." लेकिन बच्चे टीवी पर सब कुछ नहीं देखते. इनसाइट के अधिकारियों का मानना है कि दो से तीन वर्ष तक के बच्चे सामान्य कार्यक्रमों और विज्ञापनों में फर्क जान जाते हैं. उनका मानना है कि यह बात उनके सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी पुष्ट हो जाएगी. दिल्ली की एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग के प्रमुख अजीत शाह कहते हैं, "मुझे लगता है कि बच्चों को धारावाहिकों की तुलना में विज्ञापन देखने में ज्यादा आनंद आता है."

चौथा कारण यह है कि बच्चे कुछ ही समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और ऐसे में 10 सेकेंड वाले विज्ञापन उनके मतलब के साबित होते हैं. वयस्कों की तरह वे विज्ञापन आने पर अपना ध्यान कहीं और नहीं मोड़ लेते. शाह कहते हैं, "मजेदार बात यह है कि बच्चे सारे विज्ञापनों पर ध्यान देते हैं, भले ही वह चीज उनके किसी भी उपयोग की हो या नहीं."

बच्चे विज्ञापनों को पूरा का पूरा याद रखते हैं. जब एक ही विज्ञापन रोज-रोज दिखाया जाने लगता है तो बड़ों को ऊब होने लगती है पर यह बच्चों के दिमाग पर पक्का असर छोड़ता है. मुद्रा के कृष्ण-मूर्ति कहते हैं, "मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो टीवी पर आने वाली सभी तुकबंदियां दोहरा सकते हैं; कुछ तो पूरे साउंड ट्रेक की नकल उतार सकते हैं. लेकिन वयस्कों के साथ ऐसी बात नहीं है."

विज्ञापन एजेंसियों के लोग बच्चों के इन गुणों का सिर्फ स्तुतिगान ही नहीं कर रहे बल्कि उनकी कोशिश है कि बच्चे आगे भी टीवी से चिपके रहें. इसका तरीका है: बच्चों का ध्यान खींचने के लिए विज्ञापनों में बच्चों को शामिल करना. पाथफाइंडर्स के महाप्रबंधक प्रणेश मिश्र कहते हैं, "यह काम मछली के कांटे में चारा लगाने जैसा है. अगर इसे सुरुचि-पूर्ण ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से यह बच्चों को पसंद आएगा." इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मैगी नूडल्स का विज्ञापन जिसमें अनेक भूखे बच्चों को नूडल्स दी जा रही हैं. हार्लिक्स, ब्रूस्ट और माल्टोवा के विज्ञापन भी इसी कोटि के हैं.

इस बीच, उम्मीद है कि ये दोनों अनुसंधान विज्ञापन वालों की दुनिया में हंगामा मचा देंगे क्योंकि ये एकदम नया क्षेत्र छान रहे हैं. इनसाइट के लिए इस परियोजना के प्रमुख रानू राज कहते हैं, "दुनिया में और कहीं बच्चों को लेकर बहुत अनुसंधान नहीं हुए."

लेकिन बच्चों को लेकर ऐसा अनुसंधान करना मुश्किल भी है. पहली दिक्कत तो यह है कि बच्चे अलग-अलग उम्र के हैं इसलिए उन्हें किसी एक आयु वर्ग में नहीं रखा जा

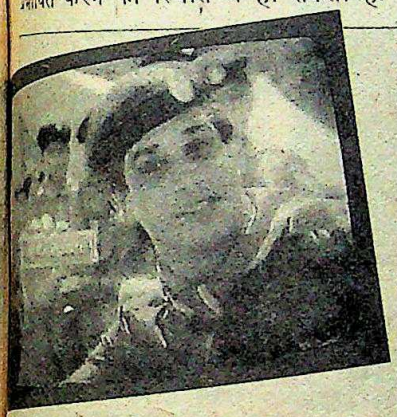

विज्ञापन एजेंसियां इस बात का प्रबंध करने में लगी हैं कि बच्चे टीवी से चिपके ही रहें. बच्चों को आकर्षित करने के लिए वे विज्ञापनों में बच्चों को शामिल करते हैं

अहमदाबाद की विज्ञापन कंपनी मुद्रा कम्यु-निकेशंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ए.जी. कृष्णमूर्ति कहते हैं, "घर का कर्ता कह सकता है कि गोदरेज फ्रिज सबसे बढ़िया है. लेकिन उसकी बेटी केल्विनेटर की प्रशंसक हो सकती है क्योंकि विज्ञापन में केल्विनेटर को 'कूलेस्ट' बनाने वाली छोटी पेंग्विन ने उसको सम्मो-हित कर रखा है. उसकी बात कोई कठोर हृदय पिता ही टाल सकता है."

विज्ञापनों से बच्चों को लुभाने के पीछे मंशा यह है कि बच्चे किसी खास ब्रांड की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकता. इनसाइट की टीम ने इसके लिए फ्रांसीसी विकास मनोवैज्ञानिक ज्यां पिगट जैसे लोगों की किताबों का भी जमकर अध्ययन किया है.

फिर बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाते. इस अनुसंधान से प्रारंभिक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करने वाले राज कहते हैं, "उनसे पूछिए कितनी बार और कितना, वे आपका मुंह ताकते रहेंगे. वे सभी चीजों का एक बार में साफ-साफ जवाब नहीं देते." बंबई और उसके उपनगरों के विभिन्न-आयु वर्ग के बच्चों के 16 समूहों को दो घंटे के 'मनोरंजन' सत्र के लिए बुलाया गया था. इनसाइट के पियुल पटनायक बताते हैं, "वह किसी पार्टी जैसा कार्यक्रम था. बच्चे वहां से जाना नहीं चाहते थे."

इन सब अनुसंधानों के कुछ प्रारंभिक निष्कर्ष निकले हैं जिनसे भारतीय बच्चों के बारे में जानकारी मिलती है:

- छह से सात: सिर्फ खिलवाड़ करने वाले, परिवार और शिक्षकों से बहुत प्रभावित.
- आठ से दस: मुख्य भूमिका निभाने वाले, मुख्य रूप से स्कूल और दोस्तों से प्रभावित.
- ग्यारह से पंद्रह: होड़ करने वाले, साथियों से प्रभावित. उम्र के इस मुकाम से परिवार की बातें न मानने का क्रम धीरे-धीरे शुरू.
- सोलह से अठारह: नौजवान, सामूहिक फैसले मानने वाले.

इनसाइट के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बढ़ते बच्चों को विज्ञापन अच्छे लगते हैं. सामूहिक साक्षात्कारों में अधिकांश माताओं ने इसे स्वीकार किया.

स्पष्ट है कि विज्ञापन जगत का जादू चल पड़ा है. इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि बच्चों पर इसका भारी मनोवैज्ञानिक असर होता है. फिल्म निर्माता शेखर कपूर कहते हैं, "मुझे यह सोचकर हैरत होती है कि जिन बच्चों को मैगी नूडल्स और रसना नहीं मिल सकती उन पर क्या गुजरती होगी." जिस तरह से विज्ञापन वाले बच्चों की ओर ध्यान दे रहे हैं, उसी हिसाब से बच्चों की समझदारी भी बढ़ रही है.

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ. के.के. कोठारी कहते हैं, "अगर मां-बाप बच्चों को असलियत नहीं बताते तो धुआंधार विज्ञानपनबाजी से हमारे मूल्यबोध गड़बड़ाएंगे ही."

विज्ञापन एजेंसियों को भी इसका पता है. लेकिन वे धंधे की मांग और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच फंस गई हैं और इन दोनों के बीच संतुलन रख पाना उनके लिए कोई बच्चों का खेल नहीं होगा.

—आनंद पी. रमन

थापर समूह

माफी फिर सजा

सरकार अपने वायदे से मुकरी

लग तो रहा था कि सरकार ने विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन के लिए ललित मोहन थापर को माफ कर दिया है. लेकिन थापर समूह की एक कंपनी पर मोटा जुर्माना ठोककर सरकार ने क्षमादान वापस ले लिया है.

देश के पांचवें सबसे बड़े औद्योगिक समूह पर सनसनीखेज छापा डालने, ललित थापर की नाटकीय गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई के दो साल बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जे.जी. ग्लास कंपनी पर 25.2 लाख रु. का जुर्माना ठोक दिया है. पिछले महीने निदेशालय ने इस कंपनी को फेरा के उल्लंघन का दोषी पाया.

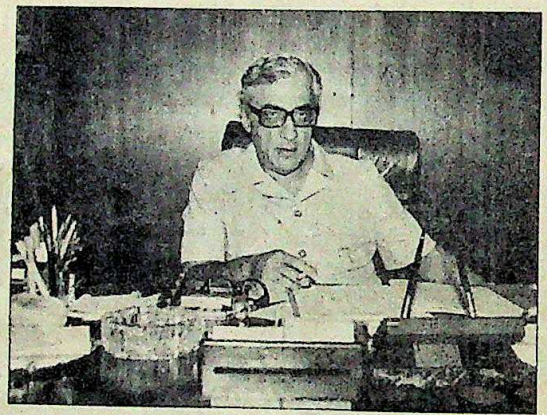

सरकार ने थापर समूह की एक कंपनी को फेरा कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी माना है लेकिन थापर कहते हैं कि वे इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे

विशेष निदेशक एल.के. सिंघवी का यह फैसला थापर समूह की पांच कंपनियों जगजीत कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, क्राम्प्टन ग्रीव्स, केसीटी ब्रदर्स और जे.जी. ग्लास को जारी 31 कारण बताओ नोटिसों में से केवल तीन से संबंधित है. आरोप था कि पांचों कंपनियों ने विदेश में कमाए 14 करोड़ रु. स्वदेश नहीं लाए. थापर समूह ने तब के वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्षमा याचना पत्र लिखकर माना था कि उन्होंने 8 करोड़ रु. स्वदेश नहीं लाए. लेकिन बाकी आरोपों से उन्होंने इनकार किया था. इस पर वित्तमंत्री ने नरमी बरतने का वायदा किया था.

लेकिन पिछले महीने का निर्णय दो कारणों से महत्वपूर्ण है. एक तो यह कि दूसरी कंपनियां यदि फेरा के उल्लंघन की दोषी पाई जाती हैं तो उन पर मोटा जुर्माना हो सकता है और दूसरा कि सरकार वी.पी. सिंह द्वारा थापर समूह से किए गए वायदे को झुठलाना चाहती है.

जे.जी. ग्लास कंपनी पर तीन आरोप थे. पहला, कंपनी ने मलेशिया में संयुक्त उपक्रम की कंपनी जे.जी. कंटेनर्स को निर्माण तकनीक और सेवाएं तो मुहैया कराईं लेकिन रायल्टी के एक करोड़ रुपए उसने स्वदेश नहीं लाए. फिर 30 लाख रुपए की कीमत के संयंत्र और मशीनरी के निर्यात के लिए भुगतान भारत में नहीं हुआ. तीसरे, कंपनी ने इस संयुक्त उपक्रम को 80 लाख रु. का ऋण दिया जिसमें से लगभग 29 लाख रु. वापस नहीं लाए गए.

इन आरोपों के जवाब में थापर का कहना था कि मलेशियाई कंपनी घाटे में होने के कारण मलेशिया सरकार को टैक्स नहीं अदा कर पाई और बैंकों ने जे.जी. कंटेनर्स के खाते सील कर दिए लेकिन सिंघवी को यह कैफियत जंची नहीं और उन्होंने जे.जी. ग्लास पर रायल्टी न वसूल पाने के लिए 20 लाख रु., निर्यात की गई मशीनरी का भुगतान स्वदेश न लाने पर 5 लाख रु. और जे.जी. ग्लास कंपनी के अध्यक्ष एस.एस. लाल पर 1.5 लाख रु. का जुर्माना कर दिया.

प्रवर्तन निदेशालय ने निश्चित रूप से कड़ा कदम उठाया है. इससे उन्हें आलोचकों का मुंह बंद करने का मौका भी मिल गया है. लेकिन थापर इन जुर्मानों से विचलित नहीं लगते. वे कहते हैं, "हमें कोई शिकायत नहीं है. उन्होंने हम पर जुर्माना किया है और हम अदालत में अपील करेंगे."

अब थापर समूह और सरकार के बीच यह लड़ाई जब अदालत में लड़ी जाएगी प्रवर्तन निदेशालय बाकी तमाम मामलों पर भी एक-एक करके फैसले करेगा ताकि बड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में उसे पर्याप्त प्रचार मिलता रहे.

—पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स

आशातीत सफलता

ऋणपत्रों के लाखों खरीदार

रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) के 593 करोड़ रु. के परिवर्तनीय ऋणपत्र जिस शोरशराबे के साथ जारी हुए, उनकी बुकिंग उससे भी अधिक हंगामेदार तरीके से हुई. तरह-तरह की अफवाहों और चर्चाओं के बीच दस दिनों के अंदर आवेदनों का अंबार लग गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज का अनुमान है कि इन ऋणपत्रों के माध्यम से 20 लाख से ज्यादा लोगों से 1300 करोड़ रु. जुटे हैं. कंपनी ने दावा किया कि आरपीएल ने अपने पहले निर्गम में जो सफलता हासिल की है उससे वह दुनिया के सबसे प्रमुख 10 निर्गमों में से एक बन गया है.

रिलायंस के बंबई कार्यालय में आवेदनों के इस अंबार की छंटाई अभी चल ही रही थी कि कंपनी के कर्ताधर्ता धीरूभाई अंबानी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई. बड़े आश्चर्यजनक तरीके से वित्त मंत्रालय ने कंपनी को पहले से तय सीमा से अधिक बुकिंग वाली राशि भी रख लेने की अनुमति दे दी. शर्त सिर्फ इतनी रखी गई कि आरपीएल को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति तीन महीने के अंदर हासिल कर लेनी होगी. इस फैसले से रिलायंस के इस निर्गम के प्रचार वगैरह के खर्च के 20 करोड़ रु. बचेंगे.

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "केंद्र के पास हमारे चार या पांच आवेदन पड़े हुए हैं लेकिन अगले चार हफ्तों तक हम उनकी मंजूरी के पीछे नहीं लगेंगे. इन चार हफ्तों में आवेदनों की छंटाई पूरी हो जाएगी."

निजी कंपनियों को आम तौर पर प्राप्त कोष में से पहले से तय सीमा से सिर्फ 15 फीसदी अधिक राशि रखने की अनुमति दी जाती है. लेकिन अगर रिलायंस ऋणपत्रों के खजाने में निवेशकों द्वारा झोंकी गई रकम में से अतिरिक्त 700 करोड़ रु. रख लेने में सफल हो गया है तो यह अंबानी परिवार के लिए एक और बड़ी 'उपलब्धि' ही है. अभी तक सरकार ने दो बहुत ही छोटे निर्गमों—ओसवाल एग्रो और सोना स्टीयरिंग के मामले में ऐसी ढील दी थी.

ऋणपत्र निर्गम की इतनी जबरदस्त सफलता का श्रेय निश्चित रूप से अंबानी की विपणन रणनीति को जाता है. इस निर्गम पर रिलायंस ने कुल 20 करोड़ रु. खर्च किए और इसकी आधी से अधिक राशि इसके जारी होने के ठीक एक महीने पहले ही खर्च की गई. अखबारों, पत्रिकाओं और रेडियो-टीवी पर विज्ञापनों की भरमार कर दी गई. दूरदर्शन पर एक मिनट वाले 70 और 60 टाइम चेक विज्ञापन तथा रेडियो पर 3480 बार विज्ञापन प्रसारित किए गए. ये सभी भाषाओं में थे.

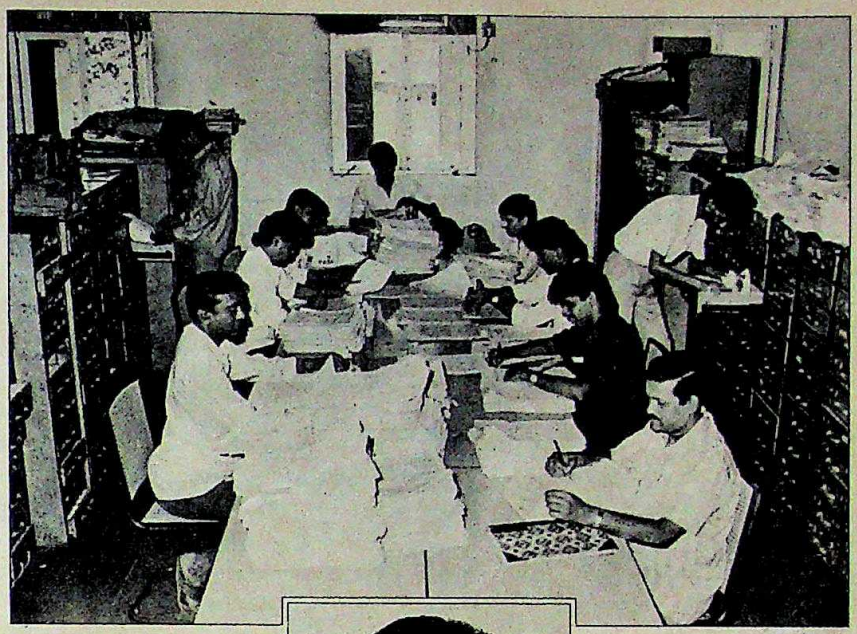

ऋणपत्रों के लिए आई अर्जियां; और (बाएं) धीरूभाई अंबानी: कामयाबी

विज्ञापन की रणनीति बाजार संबंधी विस्तृत अनुसंधान के बाद बनाई गई थी. इसके तहत पिछले कई वर्षों में आए रिलायंस के छोटे निवेशकों के पत्रों का विश्लेषण भी किया गया. ज्यादा जोर टीवी विज्ञापन पर था जिसमें परिवार का भविष्य एक निहायत खूबसूरत छोटे-से खजाने से जुड़ा दिखाया गया. लेकिन चिट्ठियों के विश्लेषण के बाद ही अखबारों के वैवाहिक और जायदाद संबंधी वर्गीकृत विज्ञापनों की नकल वाले विज्ञापन तैयार करने का ख्याल आया. ये विज्ञापन सबसे अधिक चर्चित हुए, पर रिलायंस के इस अभियान का सबसे बड़ा कमाल यह था कि इसने निवेश के लिए पहली बार निर्गम को किसी उपभोक्ता सामग्री की तरह पेश किया गया.

निर्गम के नतीजों के प्रति आश्वस्त रिलायंस ने दलालों का कमीशन 1.5 फीसदी ही रखा. आम तौर पर यह 1.5 से तीन फीसदी तक होता है. यही नहीं, अंबानी परिवार ने निवेशकों को उस दिन से ब्याज देने का फैसला किया जिस दिन उनका आवेदन मंजूर होगा. वैसे आम तौर पर उसी दिन से ब्याज दिया जाता है जिस दिन निवेशक का चेक कंपनी के दफ्तर में पहुंच जाता है. इसका अर्थ हुआ कि जिन 90 दिनों में रिलायंस निवेशकों को मंजूरी की चिट्ठी भेजेगा, उस समय तक वह ब्याज के रूप में 10 करोड़ रु. कमा चुका होगा.

लेकिन मामला इतना भर ही नहीं है. रिलायंस ने शुरू में जो जानकारियां दीं उनके अनुसार इस बार उसके ऋणपत्रों के लिए 5 लाख ऐसे लोगों ने भी आवेदन किए हैं जो अब तक शेयर बाजार से दूर ही रहे थे. अगर यह जानकारी सही है तो इससे सिर्फ रिलायंस के निवेशकों की संख्या (30 लाख से ज्यादा) में ही बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि यह काफी समय से दिक्कतें झेल रहे शेयर बाजार के लिए भी एक खुशखबरी है.

लेकिन इस शुरुआती हंगामे में यह अंदाजा भी नहीं लग सकता कि इस रिकार्ड निवेश में सामान्य निवेशकों के पैसे का कितना हिस्सा है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं का कितना.

इस भारी-भरकम अभियान से जुटे पैसे का हिसाब-किताब चाहे जो हो, एक बात तय है कि इसने अंबानी परिवार को और बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया है.

—एम.रहमान, ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सांबर

विदेशी दाल, देसी जायका

कार्टून: अजीत नैनन

इस अफलातून को रोकने के लिए वही उपाय करना होगा जो कंगारुओं के लिए किया जाता है

ऑस्ट्रेलियाई सांबर? विचित्र, किंतु सत्य. जी हां, धुर तमिलनाडु में बनने वाले सांबर का भी अब विदेशी 'कनेक्शन' हो गया है.

करीब सात साल पहले सरकार ने देश में दालों की पैदावार कम होने के कारण इन्हें आयात के लिए ओपन जनरल लाइसेंस सूची में रख दिया था. आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तुर्की जैसे देशों से करीब 300 करोड़ रु. की दालें मंगाई जा रही हैं.

लेकिन इस विदेशी 'कनेक्शन' का बढ़िया नमूना तमिलनाडु के सांबर में ही मिलता है. मसूर की दाल से बना यह चटपटा व्यंजन स्वाद में तो वैसा ही है लेकिन इसमें काफी बदलाव आ चुका है. पहले यह अरहर से बना करता था, अब इसमें ऑस्ट्रेलियाई 'दुन' मटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा है.

आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं. कुछ वर्ष पहले तक तमिलनाडु में प्रति माह 25,000 टन अरहर दाल की खपत होती थी. आज इसकी खपत एक-तिहाई कम हो गई है. होटलों और मध्यम वर्गीय घरों में इसकी जगह ऑस्ट्रेलियाई दाल इस्तेमाल होने लगी है. मद्रास में एक होटलवाला कहता है, "आज कोई भी होटल अरहर दाल से सांबर नहीं बनाता. अब यह ऑस्ट्रेलियाई 'दुन' मटर से ही बनाया जा रहा है."

इसकी कई वजहें हैं. इनमें कीमत सबसे प्रमुख है. तूतीकोरिन में कई होटल चलाने वाले 62 वर्षीय नांबी रेड्डियार बताते हैं, "ऑस्ट्रेलियाई दाल सात रु. किलो मिलती है जबकि अरहर 14 रु. तक में. महत्वपूर्ण यह है कि पकने के बाद दोनों के स्वाद में खास फर्क नहीं होता. इसीलिए सभी होटल सांबर के लिए अब यही दाल ले रहे हैं. और हमारे ग्राहकों को भी कोई शिकायत नहीं."

तमिलनाडु में विदेशी दालों की घुसपैठ पांच साल पहले हुई जब यहां देसी दालों की कीमत प्रति किलो चार रु. से बढ़कर आठ रु. तक पहुंच गई. यहां गुजरात से अरहर दाल आती थी. जब उसकी कीमत भी 10 रु. किलो हो गई तो लगने लगा कि ज्यादातर तमिल खाने में अपना सबसे प्रिय सांबर भी नहीं जुटा पाएंगे.

तभी कुछ उद्यमियों ने अरहर की जगह सस्ती चीज लाने की सोची. मद्रास के लायन ऑटोमोबाइल्स के 38 वर्षीय षण्मुगम पिल्लै सुब्रह्मण्यम ने पाया कि दालें ओपन जनरल लाइसेंस वाली सूची में हैं और इनका आसानी से आयात किया जा सकता है. उन्होंने सभी जगह सस्ती दाल की संभावनाएं तलाशीं. ऑस्ट्रेलियाई 'दुन' मटर उन्हें उपयुक्त लगी. वैसे इसका उपयोग पशुओं के चारे में होता था लेकिन मनुष्य भी इसे खाते थे. सबसे बढ़िया बात यह कि 10 फीसदी सीमा शुल्क देने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई मटर की 100 किलो वाली बोरी 600 रु. में बैठती.

पांच वर्ष पहले सुब्रह्मण्यम ने आयात लाइसेंस बनवाया और 800 टन ऑस्ट्रेलियाई 'दुन' मटर मंगा लिया. मिल में दाल के रूप में दलवाकर उन्होंने इसे बाजार में बेचना शुरू किया. शुरू में मिल वाले विदेशी मटर की दलाई करने में हिचकते थे. पर कीमत में भारी फर्क के अलावा इसकी दलाई अरहर से आसान है. तूतीकोरिन में आठ साल से दाल मिल चलाने वाले 62 वर्षीय एस. गुरुसामी नाडार कहते हैं, "अरहर को तो पहले सूखने के लिए फैला देना होता है. फिर उस पर थोड़ा पानी छिड़ककर तीसरे या चौथे दिन दलाई होती है. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मटर में इतना झंझट नहीं."

और जल्दी ही सुब्रह्मण्यम हर महीने 800 टन मटर मंगाने लगे. कुछ और लोग भी इस धंधे में उतर आए. पिछले साल तूतीकोरिन बंदरगाह पर ही ऐसा 60,000 टन मटर उतारा गया. इस साल यहां 96,000 टन मटर उतरने की उम्मीद है.

तूतीकोरिन दरअसल इस नए व्यवसाय का केंद्र बन गया है. इसका एक कारण मटर आयात करने वाले एक प्रमुख व्यवसायी के शब्दों में, "हमने देखा कि मद्रास में जरूरी प्रमाणपत्र पाने में महीनों लग जाते हैं. तूतीकोरिन में यह रातोरात मिल जाता है. इसका कारण शायद इस बंदरगाह का छोटा होना है." एक कारण शायद यहीं से कारोबार करने वाले नाडार जैसे उद्यमियों का व्यापार तेजी से बढ़ना भी है. वे कहते हैं, "पहले मैं दिन में 40 बोरे अरहर दाल (एक बोरे में 100 किलो) तैयार करता था, अब 100 बोरे 'दुन' मटर की दाल तैयार करता हूं."

आज ऑस्ट्रेलियाई मटर तमिलनाडु से अरहर की जड़ खोदने में लगा है. अब यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या तमिलनाडु का किस्सा दूसरे राज्यों में भी दुहराया जाएगा.

इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता. कुछ हफ्ते पहले यूएसए ड्राई पी ऐंड लेंटिल कौंसिल के दक्षिण एशिया कार्यालय ने अमेरिका में पैदा होने वाले मटरों का जोरदार प्रचार अभियान शुरू किया है. संगठन के दिल्ली प्रतिनिधि शकुन दलाल यह अभियान शुरू करने का कारण बताने से इनकार करते हैं. लेकिन संगठन की योजना अमेरिका के सस्ते मटर को भारतीय बाजार में घुसाना ही है. वह दिन शायद दूर नहीं जब ऑस्ट्रेलियाई 'दुन' मटर की तरह अमेरिकी मटर भी भारतीय घरों में इस्तेमाल होने लगेगा.

—एस.एच. वेंकटरमनी और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

उत्साह का ज्वार

चौतरफा अच्छी खबरें

देश के शेयर बाजारों में अचानक ही उत्साह की लहर चल पड़ी है. नए शेयरों और ऋणपत्रों के लिए सीमा से ज्यादा पैसा लगा दिया गया है और बाजार में उछाल आ गया है. पिछले कुछ हफ्तों से धीरे-धीरे चढ़ने वाली शेयरों की कीमतें पिछले पखवाड़े आसमान छूने लगीं. इकानामिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक 5 सितंबर को 275 पर पहुंच गया. इस तरह इसने इस वर्ष 8 जून के अधिकतम अंक 272.8 को भी पीछे छोड़ दिया.

बाजार के इस तेवर की कई वजहें हैं. यह तो स्पष्ट ही है कि 593 करोड़ रुपए के रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के इश्यू को भारी कामयाबी मिली है. कुछ अनुमानों के मुताबिक उनकी बिक्री 1,200 करोड़ रुपए की सीमा भी पार कर चुकी है.

फिर, सरकार के वित्तीय संस्थान भी

चार्ट: बी.के. शर्मा

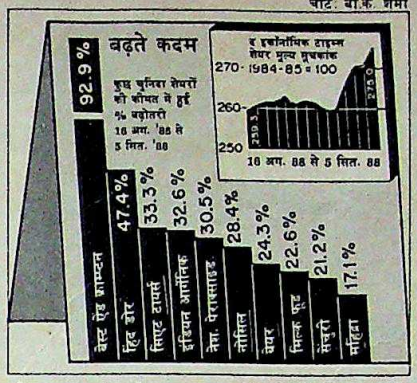

जोरदार ढंग से बाजार में उतरे हैं. उनके खजाने भी भर गए. मिसाल के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने जुलाई में सस्ती यूनिटें बेचकर 2,000 करोड़ रुपए बटोर लिए. उधर जीवन बीमा निगम का व्यापार भी हाल में 35 फीसदी की दर से बढ़ा है.

इस सबसे शेयर बाजार के अधिकारियों के चेहरे स्वाभाविक है, खिल उठे हैं. दलालों द्वारा लगाए जाने वाले दैनिक पड़ते घटाकर और किए जा सकने वाले धंधे की वित्तीय सीमा तीन गुना बढ़ाकर उन्होंने अपनी तरफ से बाजार में उत्साह बनाए रखने की भरसक कोशिश की.

शुरू में ही शेयरों की कीमतें चढ़ने के रास्ते में ज्यादा बाधा नहीं थी क्योंकि तुरतफुरत मुनाफा कमाने के चक्कर में तेजड़िये बाजार में कूद पड़े थे, और वह भी खास तौर से अहम शेयरों की खरीद के लिए. पर इस उछाल को रोकने के लिए वित्तीय संस्थान कूद पड़े. पिछले दो हफ्तों में धंधा खासा तेज हुआ.

कुछ विशेषज्ञों का अभी भी यही मानना है कि तेजी का मौजूदा दौर संस्थानों की भारी खरीदारी की वजह से ही है. मानसून की अच्छी संभावनाओं और इस साल कंपनियों के अच्छे कामकाज के बावजूद कीमतों में आई तेजी से छोटे निवेशक बहुत प्रभावित नहीं हैं. और क्योंकि वित्तीय संस्थान खरीद के तुरंत बाद शेयरों को हासिल करने पर जोर देते रहे इसलिए बाजार में शेयरों की कमी बनी हुई है.

पर यह सवाल कायम ही है कि बाजार किधर जा रहा है. क्या तेजड़ियों का बोलबाला जारी रहेगा? जून में शुरू हुए उतार-चढ़ाव वाली तेजी के दौर के बाद भी मौलिक परिवर्तन नहीं आया है. लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल बाजार को फिर जमीन पर ला सकता है. वैसे, फिलहाल तो बहारों के दिन ही हैं.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	नीचा	बंद 5.9.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
ग्लोक लेलैंड	51.25	30.25	49.00	4.25 +
एसोसिएटेड सीमेंट	265.50	128.50	255.00	24.00 +
एटलस कोप्को	63.50	33.50	50.50	1.50 +
एशियन पेंट्स	176.25	128.75	175.00	12.50 +
बजाज ऑटो	520.00	187.50	265.00	—
बड़ौदा रेयॉन	282.50	140.00	239.00	4.00 +
बाटा इंडिया	77.25	50.50	64.00	0.75 —
बारत फोर्ज	147.00	101.00	141.00	11.00 +
बिरला जूट	47.00	32.25	43.50	—
बी प्लास्ट	125.00	28.00	36.00	4.00 —
बॉम्बे डाइंग	159.50	94.00	110.00	4.00 —
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	97.50	3.00 +
बुक बांड	98.50	75.00	97.50	13.00 —
चेंबूर सिमेंट	1060.00	617.50	1045.00	122.50 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	68.00	3.50 +
कोलगेट	252.50	160.00	246.25	23.75 +
कायनामिड	52.00	33.00	41.50	4.50 +
डीसीएम	47.50	28.00	36.50	2.75 +
इनरन	86.50	66.00	70.00	1.00 —
ईआई होटल्स	54.00	38.00	50.00	—
एकार्ड्स	57.00	37.00	50.75	4.00 +
फिलिप्स कैबल्स	435.00	237.50	270.00	15.00 +
फूड स्पेशिलिटीज	149.50	93.50	149.00	18.00 +
गरवारे नाइलोन	49.00	20.00	46.00	3.25 +
जी.ई. सिपिंग	33.75	20.80	29.50	1.50 +
गुजरात स्टेट फर्टि.	149.00	75.00	147.50	3.50 +
हिंडाल्को इंडिया	111.00	81.50	106.00	1.75 +
हिंदुस्तान एल्युमिनियम	139.00	73.00	101.00	3.50 +
हिंदुस्तान मिक्स	540.00	332.50	540.00	20.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	90.00	10.00 +
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	72.25	4.00 +
हिंदुस्तान मोटर्स	29.25	15.80	26.20	0.20 —
आई.ई.एल.	43.75	31.00	37.00	3.50 +
इंडियन आर्गेनिक	33.00	15.00	31.50	3.00 +
इंडियन रेयॉन	75.00	46.00	67.00	0.75 +
इडुल	223.75	133.75	168.75	15.00 +
इंगरसॉल-रैंड	335.00	205.00	275.00	10.00 +
आई.टी.सी.	46.75	30.00	45.00	5.00 +
जे.के. सिंथेटिक्स	74.00	45.50	73.00	2.75 +
काइनेटिक इंजी.	285.00	161.25	242.50	15.00 +
किर्लोस्कर क्युमिस	59.00	48.00	57.00	1.00 +
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	290.00	15.00 —
लारसन-टुब्रो	122.00	75.50	109.50	6.00 +
लिप्टन	67.00	52.00	65.50	2.50 +
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	12.00	1.50 +
मदुरै कोट्स	77.00	59.00	71.00	1.25 +
महिंद्रा-महिंद्रा	66.50	48.50	65.00	6.50 +
मिल्क फूड	190.00	72.50	190.00	30.00 +
मोटर इंडस्ट्रीज	630.00	447.50	620.00	40.00 +
मुकुंद आयरन	97.00	72.50	90.00	2.50 +
नेशनल आर्गेनिक	640.00	390.00	632.50	132.50 +
निरलॉन	16.00	5.00	8.25	0.25 +
ओरके सिल्क मिल्स	51.00	17.00	28.00	4.50 +
पेट्रकों इलेक्ट्रॉनिक्स	37.00	24.50	29.00	0.50 —
फाईजर	79.50	50.00	61.00	7.00 +
प्रीमियर ऑटो	39.50	23.00	30.50	1.00 —
रैनबेक्सी	120.00	68.00	70.00	2.00 +
रेमंड	96.00	41.50	57.50	5.75 +
रॉकिट ऐंड कोलमैन	227.00	175.00	221.00	6.00 +
रिलायंस इंडस्ट्रीज	231.00	69.00	205.00	6.00 +
शॉ वैलेस	132.00	50.50	55.50	2.50 —
श्रीराम फाइबर्स	62.50	32.50	47.75	7.75 +
सीमेंस इंडिया	80.00	56.00	80.50	10.50 +
एसकेएफ बैयरिंग्स	1541.00	1058.00	1460.00	35.00 +
स्पिक	60.25	23.50	48.00	0.60 —
टाटा स्टील	907.50	568.75	885.00	60.00 +
टेल्को	710.00	340.00	700.00	26.25 +
वाम आर्गेनिक	103.00	75.00	93.50	11.50 +
वोल्टास	355.00	225.00	345.00	2.50 +
विम्को	24.00	11.00	17.00	3.00 —

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिकी मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	11.7051	11.5728
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1198	1.1060
बहरीन	दीनार	1	37.8820	37.8001
बांग्लादेश	टका	100	45.8128	45.7720
कनाडा	डालर	1	11.7796	11.6421
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0485	2.0257
मिस्र	पौंड	1	6.9823	6.9001
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3447	2.2857
हांगकांग	डालर	1	1.8599	1.8409
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0843	0.8000
ईरान	रियाल	100	20.0863	20.0000
इटली	लीरा	100	1.0360	1.0000
जापान	येन	100	10.9890	10.7181
केन्या	शिलिंग	1	0.7732	0.7226
कुवैत	दीनार	1	50.3536	50.2900
मलेशिया	डालर	1	5.4814	5.4242
मारीशस	रुपया	1	1.0240	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6430	0.6100
हालैंड	गिल्डर	1	6.9711	6.8943
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7959	0.7303
सिंगापुर	डालर	1	7.1295	7.0550
स्पेन	पेसो	1	0.1160	0.1001
श्रीलंका	रुपया	1	0.4384	0.4040
स्वीडन	क्रोना	1	2.2667	2.2406
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.3313	9.2315
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1375	0.1101
थाईलैंड	बहत्त	100	56.6732	56.6160
ब्रिटेन	पौंड	1	24.7280	24.5912
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	14.5243	14.3781
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.3968	3.3530
सोवियत संघ	रूबल	1	22.5831	22.4928
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.0084	7.8064

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 7.9.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

छाया लेख: रघु राय

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मल्लिकार्जुन मंसूर

खयाल गायकी के धुरंधर

मल्लिकार्जुन मंसूर '30 के दशक के शुरू से शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को अपने अनूठे खयाल गायन से मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं. ध्रुपद के बाद खयाल ही शास्त्रीय संगीत का विशुद्ध रूप है. कार्यकारी संपादक ***इंद्रजीत बधवार*** *अपने इस लेख में छह दशकों की उनकी लंबी संगीत यात्रा का वर्णन कर रहे हैं. यह भारतीय कला और संगीत की महान हस्तियों पर लेखों की शृंखला की अगली कड़ी है.*

इस अठहत्तर वर्षीय कृशकाय व्यक्ति की चमकदार आंखें अपार ऊर्जा से दमकती रहती हैं. जब वे हंसते हैं तो लगता है आसपास का वातावरण दामिनी की दमक से दीप्त हो उठा है. जब वे गाते हैं तो उनका गुहा सदृश मुख चेहरे पर हावी हो जाता है. उनके संगीत की कोई उम्र नहीं और न ही उसमें किसी तरह का खुरदरापन या शिथिलता है. वे जब गाना शुरू करते हैं तो लगता है मानो संगीत सरिता का अजस्र प्रवाह कभी नहीं थमेगा.

पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनते समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के श्रोता बहुधा सातत्यता और कालातीत होने के एक अलौकिक अनुभव से गुजरते हैं. मंसूर खयाल के सबसे पुराने, और शायद सबसे अधिक रूढ़ शैली के गायकों में से एक हैं. उनकी गायकी तकनीक ने न सिर्फ गायकों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रभावित किया है बल्कि कंठ और सुर के बीच की कुछ सीमाओं को भी तोड़ा है.

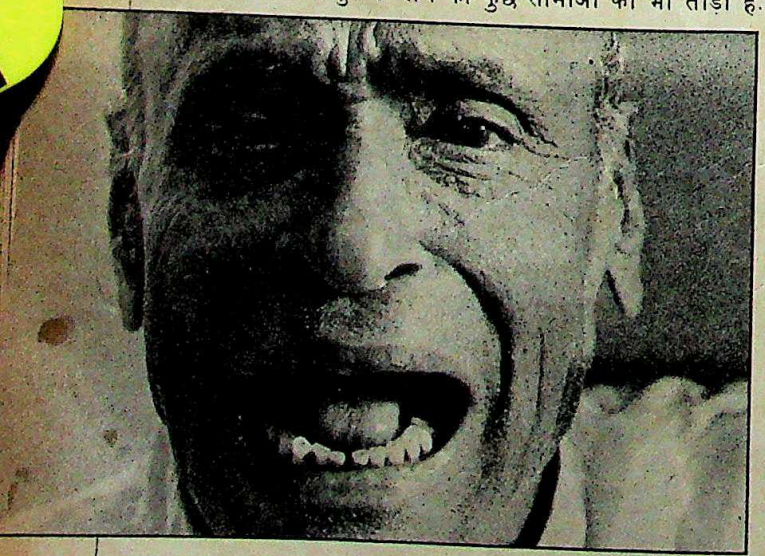

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंसूर के संगीत की न कोई उम्र है, न उसमें ख़ुरदरापन या शिथिलता है

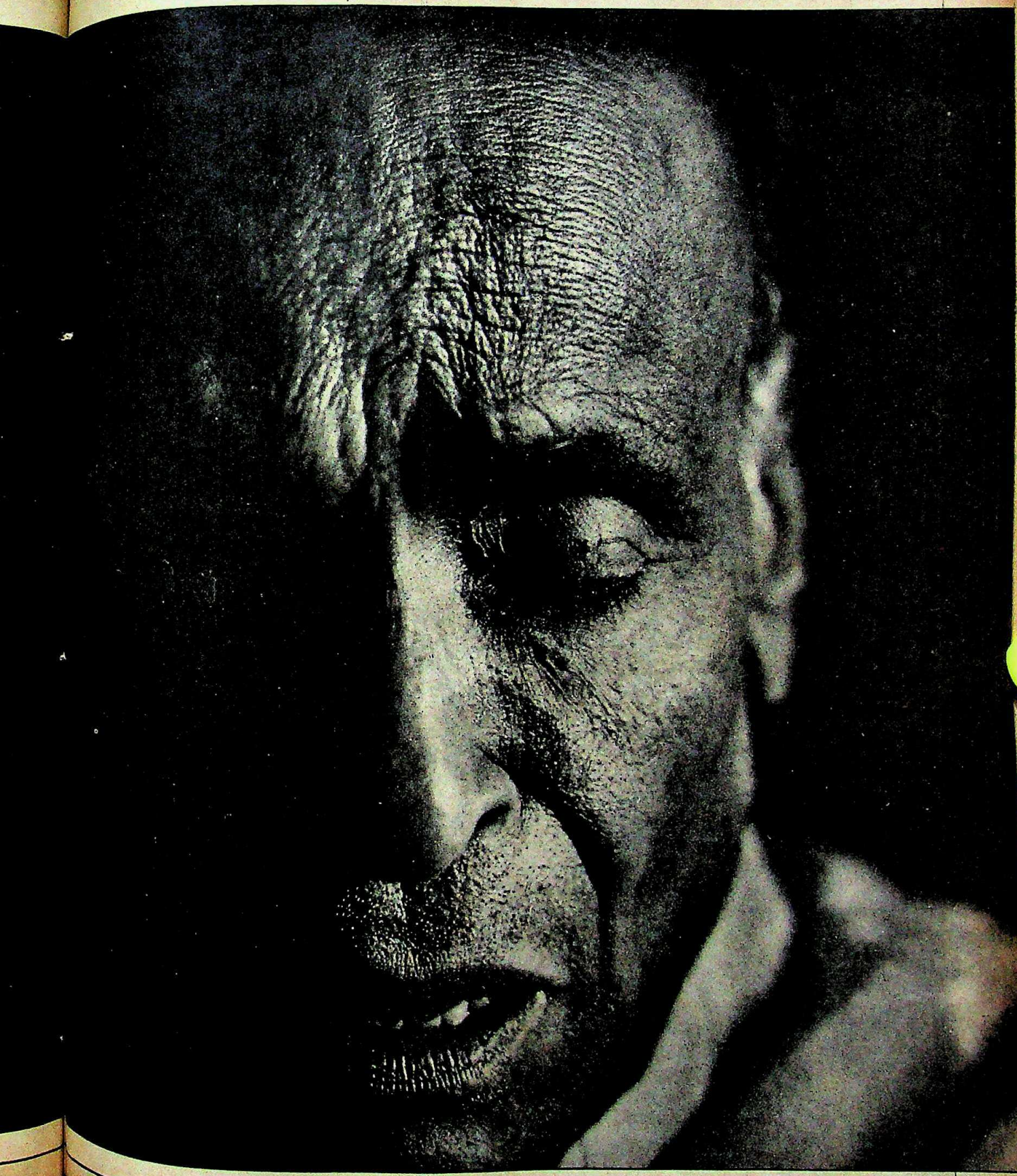

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विलायत खां जैसी संगीत की हस्तियों ने मंसूर के संगीत का अपने सितार में भी इस्तेमाल किया है.

मंसूर की विशेषता है उनकी पारिवारिक जड़ें. वे कर्नाटक के धारवाड़ में साधारण-सी साज-सज्जा वाले छोटे मकान में दो पुत्रियों और एक पौत्र के साथ रहते हैं. उनकी गर्मजोशी और यहां तक कि जीवन शैली से भी झलकता है कि वे हैं क्या: एक सीधे-सादे व्यक्ति. वे किसी मशहूर संगीत घराने में पैदा नहीं हुए और न ही उनके परिवार को किसी राजा का संरक्षण मिला. फिर भी अपने जीवन काल में ही वे बडी हस्ती बन गए. लेकिन बड़े आदमी का कोई प्रतीक उनके पास नहीं है. उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वे जो कुछ कमाते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के बीच बांट देते हैं. जैसा कि उनके एक शागिर्द कहते हैं, "वे सच्चे फकीर हैं. खयाल के फकीर."

मंसूर नामक छोटे गांव से उनका नाता बराबर बना हुआ है. उन्होंने अपना उपनाम इसी गांव के नाम पर रखा है. यहीं वे पैदा हुए थे. उनके भाई कालप्पा, लिंगप्पा, शंकरप्पा और उनके परिवार एक-दूसरे से सटी दो झोंपड़ियों में रहते हैं. गांव के लोगों को मंसूर पर नाज है. वे उन पर प्यार की वर्षा कर देते हैं. लेकिन वे उनकी पूजा नहीं करते. आखिर मंसूर हैं तो उन्हीं में से एक. वे भी तो बचपन में गांव की कीचड़ भरी गलियों में नंगे पांव खेलते थे.

वे धारवाड के अपने फ्लैट में नारियल के रेशे से बनी एक चटाई पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और पान गुलगुला रहे हैं. लगातार बीड़ी भी पीए जा रहे हैं. बाहर हो रही अहर्निश वर्षा रात्रि का सन्नाटा भंग कर रही है. बगल के कमरे में उनकी बड़ी बेटी उनके पौत्र गंगा को लोरी सुना रही है. यह किसी भूली-बिसरी कन्नड़ धुन की मधुर अनुगूंज है. मंसूर के सांसारिक जीवन के स्मृतिचिन्ह और ट्रॉफियां उनके शयनकक्ष की दीवारों पर जड़ी हुई हैं. दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ उनकी तस्वीरें, 1970 में पद्मश्री, 1976 में पद्मभूषण, 1981 में कालिदास सम्मान और कार्यक्रमों के निमंत्रण (उन्हें एक कार्यक्रम के लिए 10,000 से 20,000 रु. के बीच मिलते हैं और वे एक साल में चार से ज्यादा कार्यक्रम नहीं करते). उनके दो ताजा एचएमवी कैसेट—राग यामिनी बिलावल, भीगडा, खयाल विलंबित, विभास, ललिता-गौरी—एक साल से भी कम समय में 2,000 से ज्यादा बिक गए. उनके 10 एलपी और 5078 आरपीएम बार-बार जारी किए जाते हैं.

मंसूर के गले की कड़क हंसी में बदल जाती है, "तो, आप मेरा अंतरंग जानना चाहते हैं?" वे पूछते हैं, "इस बारे में कि मैं अपने संगीत या संगीत के बारे में क्या महसूस करता हूं?" वे हंस पड़ते हैं. फिर सिर हिलाते हुए कहते हैं, "आप जितना ज्यादा जानेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उतना ही कम बोलेंगे. भरी हुई गागर नहीं छलकती."

मंसूर का विश्वास है कि आज वे खयाल गायन की जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसमें दैवी प्रेरणा और अनुकूल परिस्थितियों का बहुत बड़ा

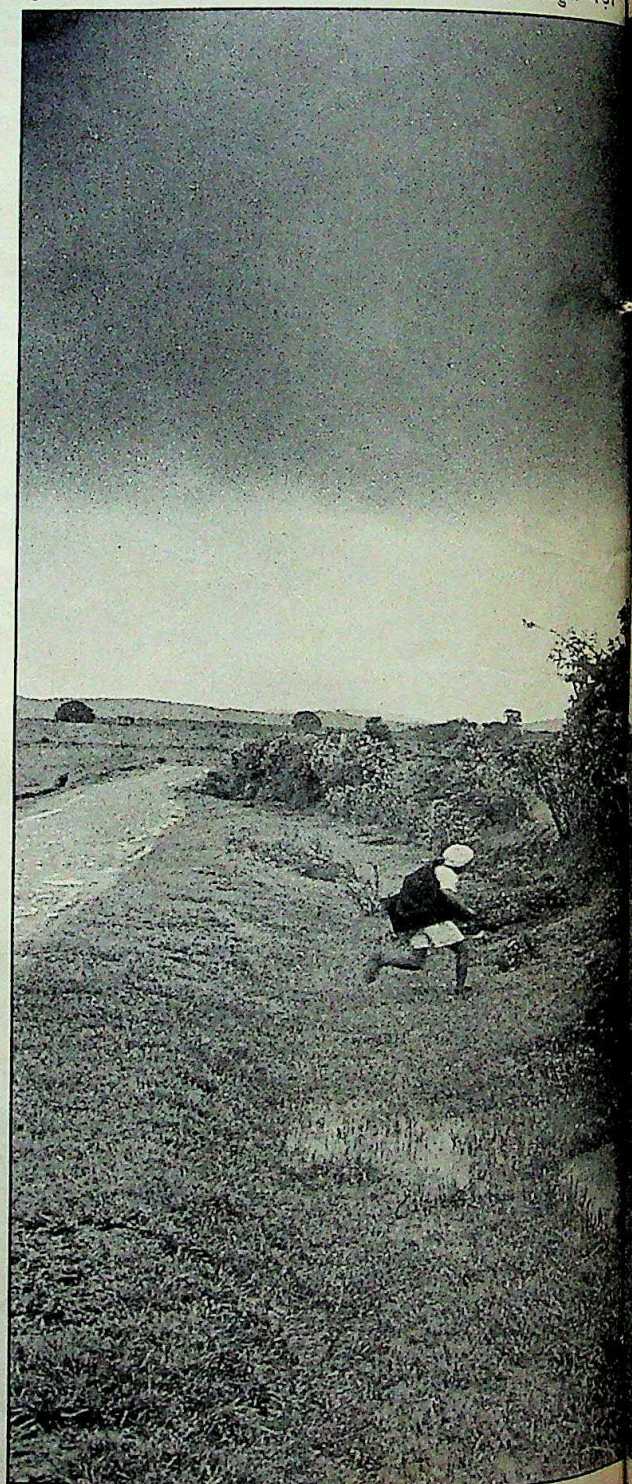

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ा रहा है. और शायद इन्हीं घटनाओं के भीतर उनकी नियति,
ी अंतस्थ यात्रा की कहानी बंद है.
मूर कहते हैं, "आप नहीं जानते, संगीत के प्रति प्रेम कैसे शुरू
ता है. आपको कभी नहीं मालूम होता कि क्यों और कब यह प्रेम
ो ही जाता है. यह सभी वेदनाओं में सबसे ज्यादा मधुर होता है."
न ने उन्हें शायद उस समय प्रेम हुआ जब वे 10 साल के थे,

वे न तो किसी बड़े संगीत घराने में पैदा हुए, न ही किसी की सरपरस्ती उन्हें मिली. जीवनकाल में ही वे संगीत के धुरंधर बन गए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शायद उससे भी पहले. लेकिन उन्हें अभी भी याद है कि उन दिनों वे अब्दुल करीम खां, आगरा के नट्टन खां और भास्कर बाखले की एचएमवी रिकार्डिंग बार-बार बड़े चाव से सुना करते थे. "उस समय मैं और कोई बात सोचता ही नहीं था. मेरे 10 साल के होने तक इन महापुरुषों ने मुझे रास्ता दिखा दिया था."

उनके पिता पटवारी थे. मंसूर उनके आठ बच्चों में से एक हैं. हालांकि पिता उनसे कहा करते थे कि रिकार्ड और घुमक्कड़ चारणों के गाने सुनने में समय बरबाद न करें, इसके बावजूद वे 10 साल की उम्र में घर से भाग गए और घुमक्कड़ कलाकारों की मंडली में शामिल हो गए. वहां उन्होंने हारमोनियम बजाना और शास्त्रीय गायन सीखा. वे जिस मंडली में शामिल हुए उसमें लोक गीत गायन या सुगम शास्त्रीय गायन नहीं बल्कि राग गाने की परंपरा थी.

एक बार जब वे कर्नाटक के बागलकोट में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे तो उन पर ग्वालियर घराने के संगीताचार्य नीलकंठ आलोड़मठ की नजर पड़ी. उस समय मंसूर ने किशोरावस्था में प्रवेश किया ही था. उन दिनों की परंपरा के मुताबिक आलोड़मठ ने मंसूर को प्रशिक्षण के लिए मीरज बुलवा लिया. मंसूर कहते हैं, "वहां मैंने सीखना शुरू कर दिया. पहली बार मैंने समझना शुरू किया."

अब वे एक सच्चे शागिर्द थे. वे गुरु के घर का ध्यान रखते, उनके कपड़े धोते और पानी लाते. "वे मुझे अपने बेटे की तरह प्रेम करते. मैं उनके चरणों में बैठकर संगीत सीखता. रोजाना तड़के 4 बजे रियाज शुरू होता और तीन घंटे तक चलता रहता. मैं बिलकुल शुरू से सीख रहा था. आवाज का अभ्यास, स्वरों का आरोह-अवरोह, मिश्रित स्वर, आवाज में स्पंदन सब कुछ." जो कुछ सिखाया जाता, वे झट सीख लेते. "एक साल के भीतर मैंने समूचे सुर को दृष्टिगत करना सीख लिया. मैं उनकी बारीकियां समझ सकता था."

गुरु के पास वे छह साल तक रहे. वे तब 18 साल के थे. वे याद करते हैं, "मैंने अपने जीवन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा. एक सेकेंड के लिए भी नहीं. मैं सिर्फ इतना जानता था कि मुझे गाना सीखना है. मैंने इसकी बिलकुल परवाह नहीं की कि मुझे इससे रोटी मिलेगी या नहीं या आगे क्या होगा. मुझे दूसरी किसी चीज में रुचि नहीं थी—न तो खाने में और न ही कपड़ों में. सिर्फ गाने में रुचि थी."

उनकी लगन रंग लाई. उनका नाम लोगों की जुबान पर आ गया. कार्यक्रमों में उनकी मांग बढ़ गई. बांबे म्यूजिक सर्किल ने उन पर आमंत्रणों की बरसात कर दी. एचएमवी ने 1932 में विशेष स्वर परीक्षण के बाद मंसूर के गाए गौड़ मल्हार का रिकार्ड तैयार किया.

वे मुश्किल से 28 साल के रहे होंगे कि उन्हें एक सम्मान मिला. उनके गृह कस्बे से सटे हुए गडग के संगीत प्रेमियों ने उन्हें 'संगीत रत्न' से विभूषित किया. 35 साल की उम्र में वे खयाल संगीतकार रूप में दूर-दूर तक मशहूर हो गए. कन्नड़ के मशहूर दार्शनिक ए.ए

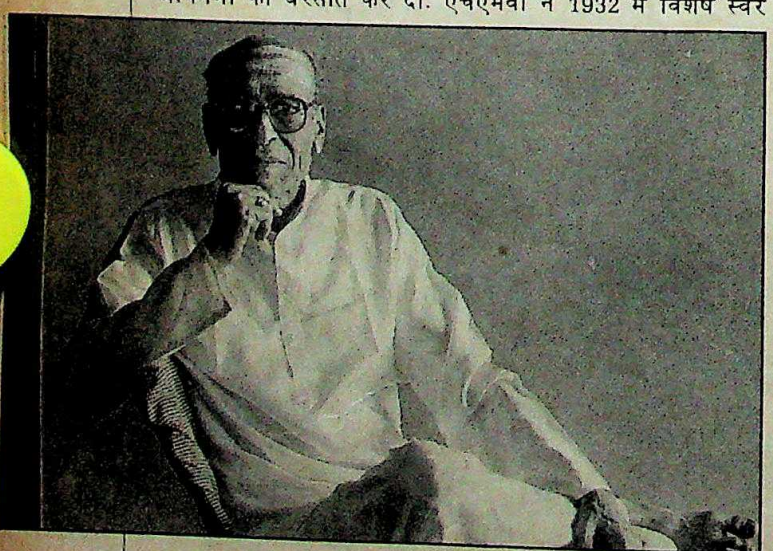

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...नारायण ने 1946 में लिखा, "मंसूर दुर्लभ राग गाने के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन साधारण राग गाते समय भी वे उस पर अपनी छाप छोड़ देते हैं. विभास, मारूविहाग, असावरी, गौड़ मल्हार जैसे राग उनके हाथ में ऐसे निकलते हैं जैसे कोई जलप्रपात."

कर्नाटक विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ए.यू.

अपनी सफलता को दिखाने के लिए मंसूर के पास कोई प्रतीक नहीं है, और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाटील कहते हैं, "मंसूर ने अपना खुद का घराना बनाया है. उन्होंने ग्वालियर घराने की महारत हासिल की और जयपुर के संगीत घराने में उसे बड़ी सुंदरता से मिला दिया. जयपुर घराने के मशहूर संगीतकार उस्ताद मंजीर खां थे." सीधे-सादे शब्दों में कहें तो राग के तीन अंग हैं— आलाप, बोल और तान. भावना को उन्मुक्त अभिव्यक्ति देने में विश्वास करने वाले जयपुर घराने में गायक राग की बंदिश के दौरान किसी भी चरण में आलाप का इस्तेमाल करता है. जबकि ग्वालियर घराना इससे ज्यादा पारंपरिक व्यवस्थित संरचना का अनुकरण करता है.

पाटील कहते हैं, "उनकी आवाज अभी भी सुरीली है. उसमें मिठास भरी हुई है. उनकी तानें सामान्य से ऊंची और तेज हैं. उनकी गैर बिशुद्ध तान मधुर हैं. ऐसा इसलिए कि वे परंपरा से अलग हट जाते हैं. परंपरा का आधार है खुले गले से गाना और नासिका तथा कंठ स्वरों का बड़ी कुशलता से मिश्रण करना."

मंसूर हंसते हैं, "आप खुले गले से कितना आ-आ... कर सकते हैं? यदि आप परंपरावादियों द्वारा सुझाए गए आआकार का अनुकरण करेंगे तो आपकी आवाज किसी फैक्टरी के सायरन की तरह निकलने लगेगी. आप इस तरीके से मिठास नहीं ला सकते."

1935 का साल मंसूर को अभी भी अच्छी तरह याद है. एक दिन शाम को वे बंबई में एक सुनार की दुकान पर बैठे दोस्तों से बतिया रहे थे. उस समय आलोड़मठ के यहां उनकी शिक्षा खत्म हो चुकी थी. लेकिन वे अभी भी हताश थे. हालांकि थोड़ा-बहुत मशहूर हो चुके थे लेकिन जानते थे कि उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है, बहुत कुछ सीखना है. उसी समय मंजीर खां दुकान पर आए. मंसूर कहते हैं, "मैंने उस महान पुरुष को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ." दुकानदार ने मंजीर खां को मंसूर की और अधिक सीखने की इच्छा बताई. मंसूर का एक रिकार्ड भी बजाकर सुनाया. मंजीर खां ने सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, "मैं इसे सिखाऊंगा."

मंसूर याद करते हैं, "मैं समझ नहीं पाया कि अभी भी धरती पर हूं या स्वर्ग में. उन्होंने मुझे दो वर्षों तक रोजाना पांच घंटे तालीम दी. वे मुझे अपने साथ गाने को कहते और इस तरह शिक्षा देते. उनका राग, स्वर, ताल और कल्पना सब कुछ अद्भुत था. मैं तो जैसे बौरा ही गया. मैंने खुद से कहा कि यह सब मेरे साथ नहीं घट सकता. मैं भयभीत हो गया कि मैं उनके जैसी राग की स्वर शुद्धि कभी नहीं सीख सकूंगा या उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकूंगा."

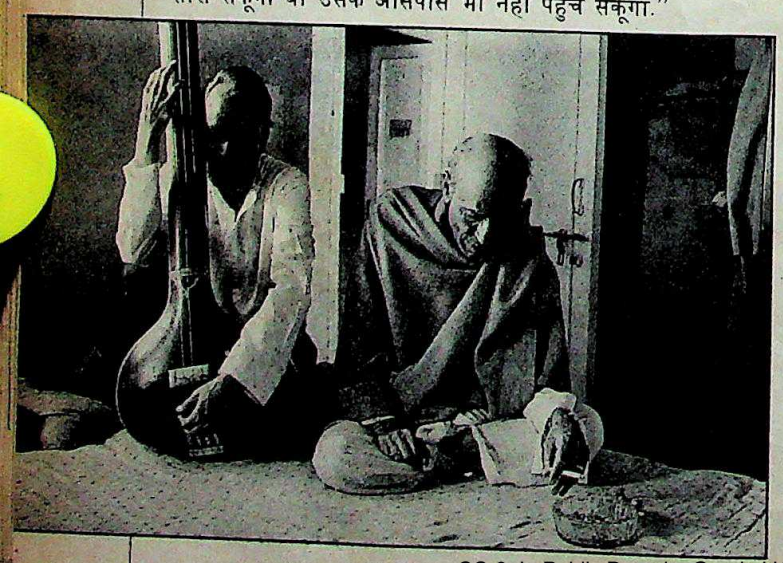

लेकिन मंजीर खां सिर्फ मुस्कराए. उन्होंने कहा, "डरो मत. मेरे साथ गाओ, तुम सीख जाओगे." मंसूर याद करते हैं, "वे जब कभी गाते तो लगता था कि समाधि में हैं. संगीत सीखना शुरू करने के ज्यादा वक्त नहीं लगा रियाज शुरू करने के चार महीने बाद मैं उनके रसों को आत्मसात करना शुरू कर दिया. वह नदी के प्रवाह

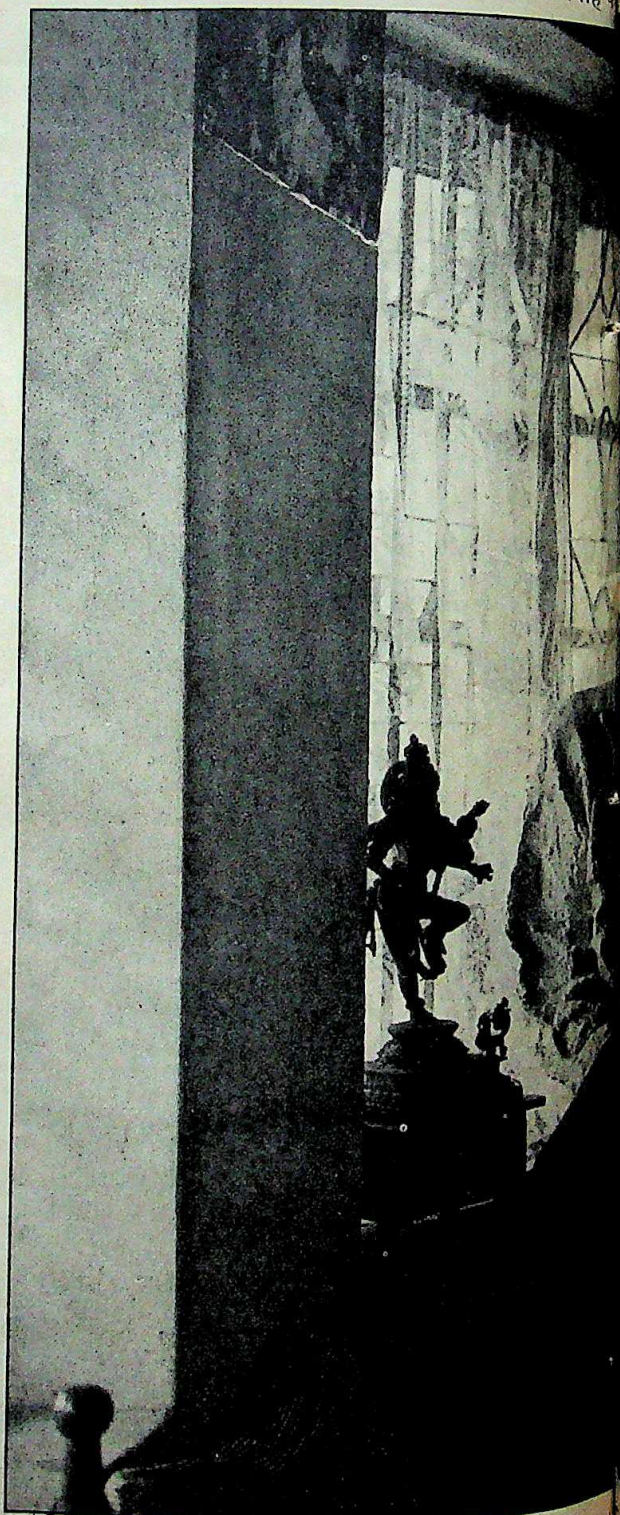

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रह था. मैंने रागों की शक्ति देखी. इसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत
ी. मैंने महसूस किया कि मै इस दरिया की तरंगों में डूब रहा हूं.''
शागिर्द मंसूर का कहना है कि सीखने के लिए, आत्मसात करने के
ए कड़े रियाज के साथ ग्रहण शक्ति भी विकसित करनी चाहिए. वे
कहते हैं कि जब उन्होंने सीखना शुरू किया तो उन्हें कुछ नहीं आता

एक दिन मंसूर ने रागों की शक्ति देखी: इसका कोई अंत नहीं, वह नदी के प्रवाह की तरह था

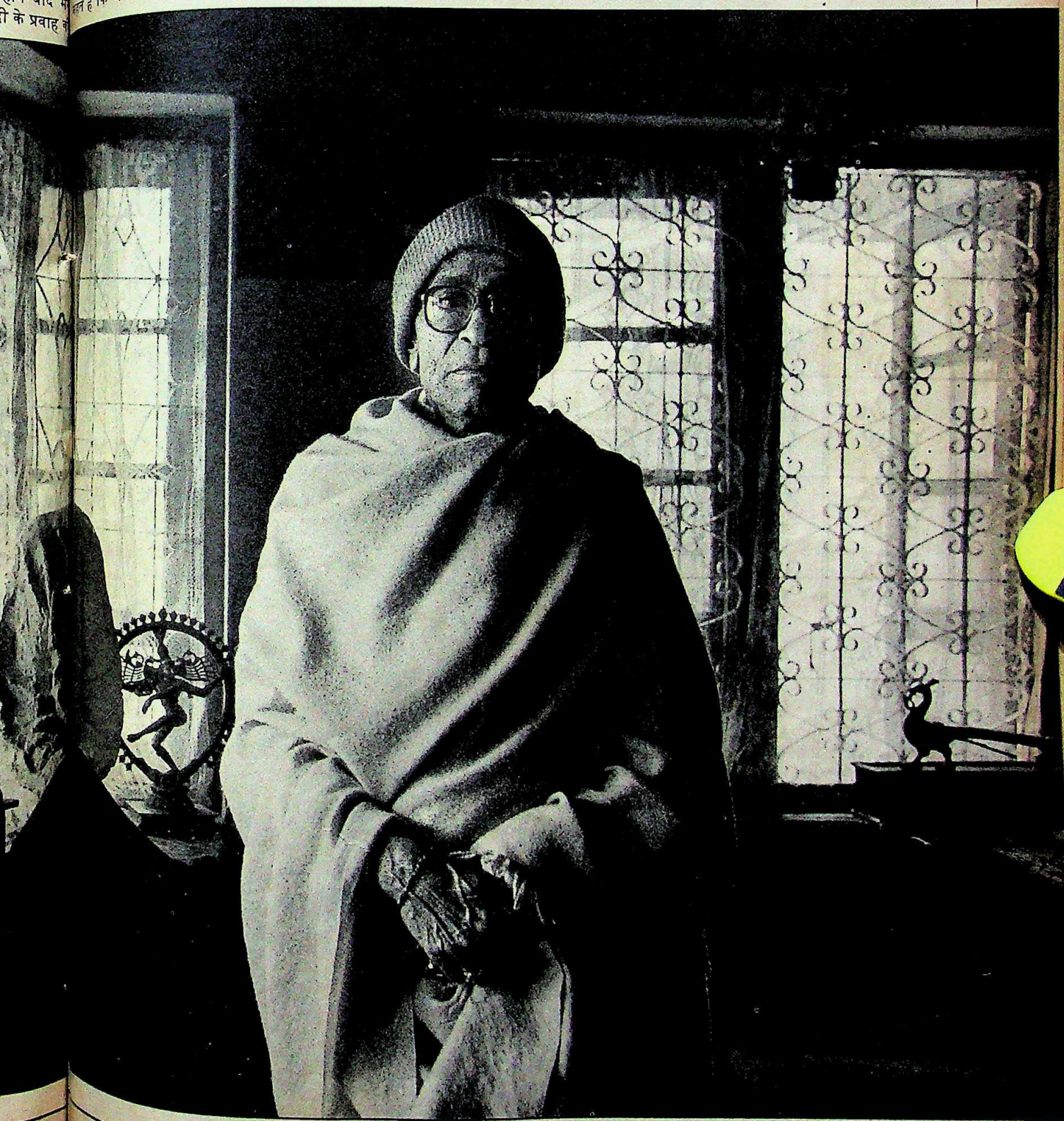

CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था. वे श्रोताओं के सामने दो घंटे तक एक ही राग गाते रहते थे. लेकिन तब उन्होंने सीखना शुरू कर दिया कि रागों को कैसे मिलाया जाए, बदला जाए, नया अर्थ दिया जाए और समय के मुताबिक ढाला जाए, बदला जाए, नया अर्थ दिया जाए और समय के मुताबिक ढाला बोल उबाऊ हो सकते हैं. लिहाजा कल्पना विलास जरूरी है. लेकिन शुद्धता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. किसी राग को ठोस व्यक्तित्व देने में आपको सक्षम होना ही चाहिए."

वे उस संगीत के और ज्यादा मजबूत और अर्थपूर्ण आयाम से रूबरू हो रहे थे जिसे उन्होंने इतना प्यार किया था. वे कहते हैं, "मेरे सामने यह तथ्य भी उद्घाटित होने लगा था कि राग दर्शन हमेशा भीतर ही रहता है. अंतस्थल में यह हमेशा गाता रहता है. कभी नहीं रुकता. आपको जानना पड़ेगा कि बाहरी दुनिया के लिए उसे किस तरह भीतर से बाहर बुलाया जाए. यह अपनी आत्मा को बाहर निकालने और उसे दूसरों के साथ बांटने जैसा है."

वे कहते हैं, "और न ही मैं महज तालीम देने के लिए हूं. शागिर्दों में सीखने की दृढ़शक्ति होनी चाहिए. अब मुझे ऐसे नौजवान नहीं मिलते जो बिलकुल लुटने के लिए तैयार हों." मंसूर आज के नौजवान शास्त्रीय संगीतकारों से प्रभावित नहीं. वे कहते हैं, "हां, उनमें तकनीकी दक्षता तो है लेकिन वजन और तपस्या नहीं है."

मंजीर खां ने मंसूर को जो अमूल्य निधि दी उनमें से एक है अपने गायन को गीत के शब्दों के अर्थ के साथ मिला देने की क्षमता. रस की सर्जना के लिए गीत में उसके अर्थ की भावना होनी ही चाहिए. "गीत और चीज का अर्थ गाने में आना चाहिए." वे बताते हैं कि कई गुरु अपने शागिर्दों को कंठ राग गाने का परंपरागत तरीका तो बताते हैं लेकिन उन्हें गाए जाने वाले शब्दों के अर्थ नहीं बताते."

मिसाल के तौर पर, राग नट में एक आलाप की इस पंक्ति को देखें. 'पियासोब तियान करनन देत.' यह वर्णमाला की तरह लगती है. इसमें अक्षरों को यों ही मिला दिया गया है. लेकिन मंसूर विभिन्न अर्थों के लिए विभिन्न संयोजनों में स्वरों को तान कर या शब्दों को आखिर से आखिर तक जोड़कर जो गाते हैं, वह यह है 'पिया सो बतियां करन न देत.' वे जिन शब्दों को गाते हैं, उनका अर्थ जानते हैं. लिहाजा वे सुर में करुणा का तत्व मिला सकते हैं.

मंसूर के जीवन पर सिर्फ संगीत के गुरुओं का ही असर नहीं पड़ा. जब वे 50 के पास पहुंच रहे थे तो मृत्युंजय स्वामी के जरिये उनमें आध्यात्मिक भाव जागा. मृत्युंजय स्वामी धारवाड़ में एक विद्या केंद्र चलाते थे. चूंकि धारवाड़ के कई कलाकार स्वामी में आस्था रखते थे, लिहाजा मंसूर भी अपनी गायन क्षमता बढ़ाने के लिए उनके पास जाने लगे. वे कहते हैं, "मैं स्वामी सेवा में बिलकुल विश्वास नहीं करता था. मुझे स्वामी की क्या जरूरत थी. आखिरकार मेरे गुरु तो थे ही. लेकिन न जाने के लिए मैं जितना ही दृढ़ निश्चय करता, लगता कोई मुझे उतनी ही ताकत से उनकी तरफ लिए जा रहा है."

कुछ दिनों तक स्वामी के पास न जाने के बाद मंसूर ने फैसला किया कि वे वहां जाएंगे. वे अभी भी यह नहीं बता सकते कि उस दिन जब उनकी आंखें स्वामी की आंखों से मिलीं तो क्या हुआ. "स्वामी जी की आंखों से आंखें न मिलने तक मैं कुछ घमंडी था. मुझे अपने पर ज्यादा अभिमान था. मैं दिखावा करता था. अपनी सफलताओं के कारण मैं अपनी प्रसिद्धि के प्रति सतर्क हो गया था. लेकिन जब उनकी दृष्टि, उनकी प्रेमपूर्ण टकटकी मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने अपना सही रूप देख लिया और कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं! उसके बाद से मेरा

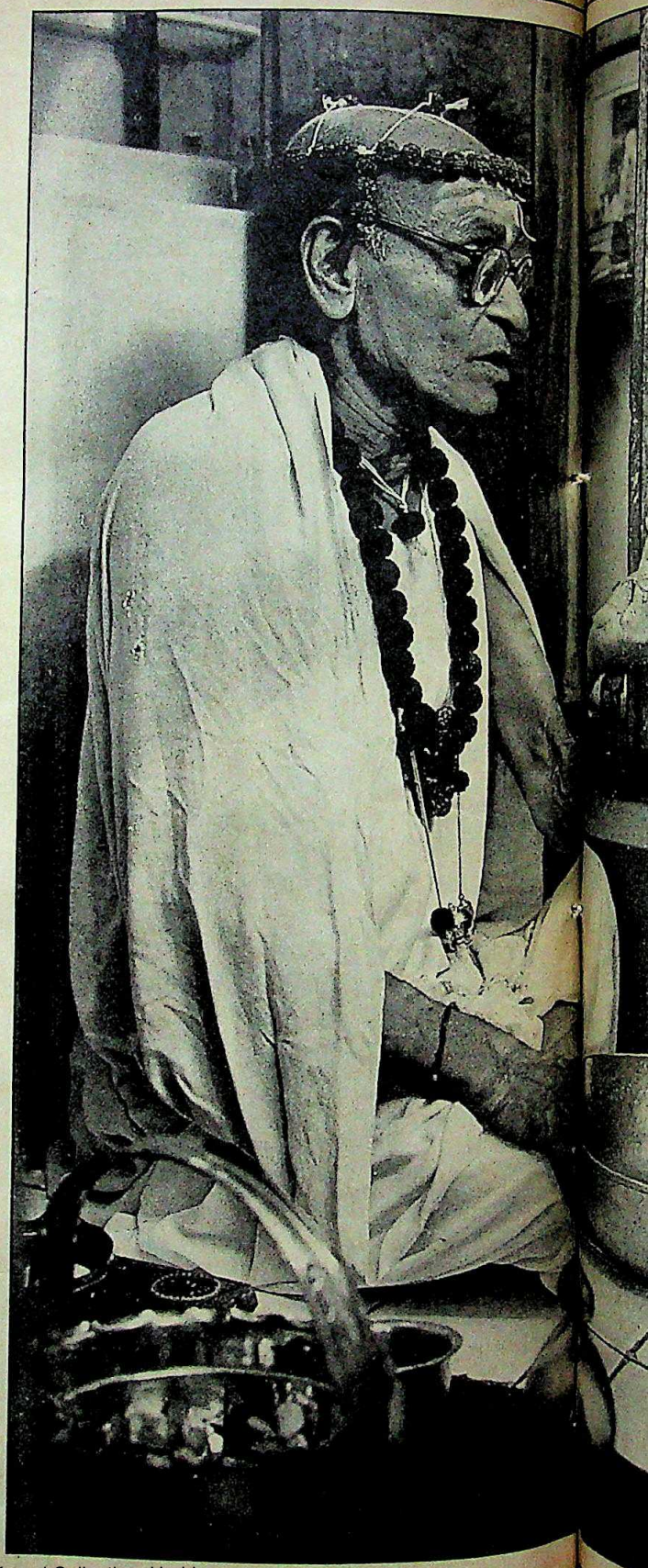

मंसूर पूजा करते हुए: प्रार्थना ने उनके संगीत को और अधिक भावप्रवण और सहज बना दिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवन बदलना शुरू हो गया, वैसे ही जैसे कि मंजीर खां से मिलने के बाद मेरा संगीत. और आज मैं उनका भक्त हूं." मंसूर ने बाद में अनुभव किया कि उनके संगीत में भी बदलाव आ रहा है. अब वे बहुत सहजता से गाने लगे. उनके संगीत से नाटकीयता जाती रही.

उनके दोस्तों ने भी यह बदलाव देखा. मंसूर कहते हैं, "मेरा मन भगवान की तरफ झुकने लगा. मैंने पाया कि प्रार्थना और संगीत इतने एकरूप हैं कि मैं अपने संगीत पर और अधिक तन्मयता से ध्यान दे सकता हूं." कुछ वर्षों बाद एक दिन मृत्युंजय स्वामी ने मंसूर को अपने पास बुलाया. मंसूर तब ऑपरेशन से उठे थे. उन्होंने देखा कि स्वामी अपाहिज हो गए हैं. मंसूर याद करते हैं, "उस अवस्था में भी उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑपरेशन के बाद मैं रात में ठीक से सोया या नहीं. फिर मेरे सिर पर हथेली रख कर मुझे आशीर्वाद दिया. मैं बच्चे की तरह रो पड़ा. एक हफ्ते के भीतर स्वामी जी की मृत्यु हो गई."

लेकिन उन्होंने मंसूर को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया. "सांसारिक चीजें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखतीं. हम जो कुछ करने आए हैं हमें वही करना है, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है. मेरा काम खत्म होता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्व तो इसे करने में है."

रोज सूर्योदय के ठीक बाद, मंसूर अपने बगीचे में होते हैं. वे पूजा के लिए बेल के पत्ते और फूल चुनते हैं. फिर वे पूजा की थाली को लकड़ी के एक छोटे से आले में रख देते हैं और नहाने चले जाते हैं. फिर सफेद कपड़े पहनकर पूजा करने बैठ जाते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं. उनके सिर पर रुद्राक्ष की माला बंधी होती है. गले में भी रुद्राक्ष की ही माला होती है. वे लिंगम पूजा करते हैं. वे चादर ओढ़कर हथेली पर रखे एक छोटे लिंगम पर अपना ध्यान लगाते हैं. वे कहते हैं कि ध्यान लगाने के कुछ क्षणों बाद लिंगम से पारलौकिक प्रकाश होता है और उनके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है. फिर वे एक प्राचीन वैदिक मंत्र पढ़ते हैं. "महादेव, विश्वंभर, जटाजिनी, त्रिनेत्र, नीलकंठ, बाघंबर, अंबर भस्म, भोलानाथ, शृंगी भाले तिलक विराजे.'

वे हंसते हुए कहते हैं, "कई लोग गाते हैं. कई लोग मरते हैं. यह संसार क्या है, हम नहीं जानते. कितनों की मृत्यु तो मेरे सामने हुई. अंत में प्रार्थना और आपका अंतस्थ जीवन ही बचा रहता है."

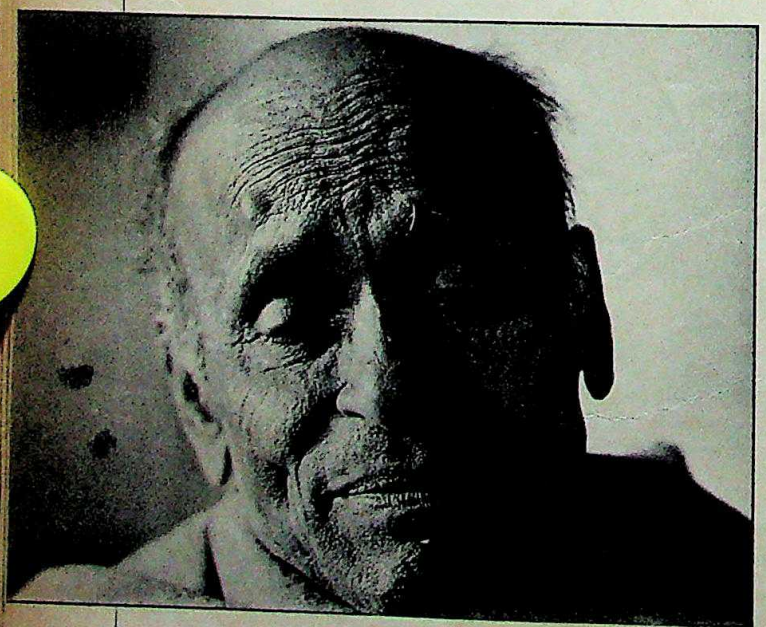

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनका संगीत अपार ऊर्जा से देदीप्यमान है, फिर भी
वह जलप्रपात की तरह बहता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंग्लैंड का दौरा

खटाई में पड़ने का खतरा

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में रंगभेद विरोधी मुहिम फिर तेज

क्रिकेट खेलने वाले यूरोपीय और गैर-यूरोपीय देशों के बीच क्षणभंगुर शांति को पिछले पखवाड़े उस समय खतरा पैदा हो गया जब इंग्लैंड के चयनकर्ताओं ने एसेक्स के सलामी बल्लेबाज ग्राहम गूच को भारत के दौरे पर आने वाली इंग्लैंड की 16 सदस्यीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना. दक्षिण अफ्रीका के साथ विवादास्पद संबंधों वाले गूच का चयन करके मानो उन्होंने रंगभेद विरोधी बर्र का छत्ता छेड़ दिया.

इस घोषणा के कुछ ही दिन बाद भारत सरकार ने एलान किया कि वह भारत के दौरे के लिए चुनी गई टीम के छह सदस्यों को वीसा नहीं देगी. ये खिलाड़ी हैं कप्तान गूच, उपकप्तान जॉन एंबुरी, एलन लैंब, किम वारनेट, फिल न्यूपोर्ट और ग्राहम डिली. ये सभी खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका में खेल चुके हैं. इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशासक पिछले सप्ताह भी असमंजस में ही थे. लंदन में टेस्ट ऐंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड (टीसीसीबी) के मुख्य अधिकारी एलन स्मिथ ने 'इंडिया टुडे' को बताया, "अब आपकी सरकार को ही अपना दिमाग बनाना है. हम इस कथित बयान की सचाई जानने की कोशिश कर रहे हैं."

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष एस. श्रीराम ने भी यह कहते हुए अपना हाथ खींच लिया, "इस पर टिप्पणी करने को क्या है? बोर्ड को सरकारी फैसला ही मानना है. मौजूदा स्थिति में सब कुछ सरकार पर ही है. यह मामला क्रिकेट का नहीं बल्कि राजनीति का है. इससे पहले सरकार का रवैया काफी लचीला रहा है जैसा कि रिलायंस कप के वक्त. लेकिन रवैया हमेशा लचीला नहीं हो सकता." खेल राज्यमंत्री मार्गरेट अल्वा ने कहा, "हमने गूच या दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखने वाले दूसरे खिलाड़ियों का चयन नहीं किया इसलिए इस दौरे की जिम्मेदारी हम पर क्यों पड़ेगी? हम रंगभेद के बारे में राष्ट्रीय नीति पर कोई छूट नहीं दे सकते."

लेकिन यह दौरा हो पाएगा इसकी संभावना बहुत ही कम है. राष्ट्रसंघ की 100 से अधिक खिलाड़ियों की काली सूची में गूच का भी नाम है. यह सूची दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी ओलंपिक समिति (एसएएनआरओसी) ने तैयार किया है. इसके अध्यक्ष सैम रामस्वामी ने गूच की नियुक्ति को 'भारी विवादास्पद' बताया है और गूच तथा ऐसे ही दूसरे खिलाड़ियों के दौरे में आने की मंजूरी न देने के भारत के फैसले की तारीफ की है. लंदन से ताजा संकेतों के अनुसार भारत दौरे पर आने वाली इंग्लैंड की टीम के 10 क्रिकेट खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से अपने संबंधों के कारण संदेह के घेरे में हैं.

हालांकि इंग्लैंड के अधिकारियों का कहना है कि समझौते में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच खेल संबंधों का ब्यौरा है और वे व्यक्तियों को अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकते. लेकिन टीसीसीबी के आलोचकों का आरोप है कि गूच को सिर्फ इसीलिए नियुक्त किया गया है ताकि भविष्य में उनकी सेवाएं ली जा सकें.

गूच के दक्षिण अफ्रीका में खेलने जाने का यह पहला मौका नहीं है. दरअसल 1981-82 में दक्षिण अफ्रीका के एक बागी दौरे में शामिल होने के लिए इंग्लैंड के विवादास्पद पूर्व बल्लेबाज ज्यॉफ बॉयकाट के साथ वे भी इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों को पटाने में सक्रिय थे. इसमें उन्होंने एलन नॉट और डेरक अंडरवुड जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी अपने चंगुल में फंसाया था.

वैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे के कारण कभी-कभार ही जिच पैदा हुई है लेकिन अब भारत के फैसले के कारण यह मुद्दा फिर चर्चित हो उठेगा. क्रिकेट की दुनिया में काले और गोरे का भेद भी पैदा हो सकता है जिसे कि इंग्लैंड टालना चाहता है. एसएएनआरओसी के रामस्वामी का कहना है कि शायद वेस्टइंडीज भी इस मुद्दे पर कठोर रुख अख्तियार करे.

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावसकर दोष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कांफ्रेंस (आईसीसी) के मत्थे मढ़ते हैं. एक संपादकीय में उन्होंने लिखा, "उन्होंने (आईसीसी) ही अपने फैसले (दक्षिण अफ्रीका से व्यक्तिगत खेल संबंधों पर) को टालकर समस्या को इस हद तक पहुंचाया है और अब समस्या उनके बस से बाहर है."

ये सब अपशकुन के ही संकेत हैं और पिछले पखवाड़े यही लगता रहा कि क्रिकेट का भविष्य भी लॉर्ड्स की गीली सुबह जितना ही धुंधला है.

—सलिल त्रिपाठी

सभी फोटो: प्रदीप भुवानी

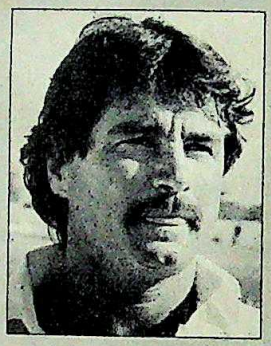

■ (दाएं से) एलन लैंब, जॉन एंबुरी और ग्राहम गूच: भारत के दौरे पर आने की अनुमति नहीं

वैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे के कारण कभी-कभार ही जिच पैदा हुई है लेकिन अब भारत के फैसले के कारण यह मुद्दा फिर चर्चित हो उठेगा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

क्वार्ट्ज़ टीवी। क्वार्ट्ज़ तकनीकी की अनूठी क्षमता से युक्त, जो
के संकेतों के एक सेकंड के दस करोड़वें भाग को भी बड़ी सूक्ष्मता
करता है ताकि आप, रंगों की आश्चर्यजनक गहनता के साथ-साथ
ट और जीती जागती तस्वीर देख सकें। आश्चर्य नहीं कि आज
ज्यादा लोग बीनाटोन क्वार्ट्ज़ टी वी खरीद रहें हैं। बीनाटोन देखिए
फैसला कीजिये।

ट्यूब पर 3 वर्ष की गारंटी.

Binatone

'QUARTZ' TVs

सकीतन वर्षों आगे

क्वार्टज़ टेक्नालॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये अपने निकटतम डीलर से सम्पर्क करें अथवा रंगीन पुस्तिका के लिए निम्नांकित पते पर लिखें:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हीरो होन्डा के सवार को आप रोक

"बस टैंक भरो, बन्द करो और भूल जाओ 800 किलोमीटर तक."

"शनिवार-इतवार मैं ज़्यादातर परिवार के संग बिताता हूँ, न कि सर्विस स्टेशन पर."

"हीरो होन्डा – क बात है!"

1985 में जब हमने हीरो होन्डा सी.डी. 100 पहली बार पेश की तो हमें पूरा विश्वास था कि यह एक अच्छी मोटरसाइकिल है। परन्तु कितनी अच्छी, हम यह नहीं जानते थे। आज हमें पूरा सन्तोष है कि हीरो होन्डा सफ़लता की मंज़िलें पार करती हुई हर कहीं छा गई है।

टैंक भरिए...और चलाते चलिए

कुछ लोग इसकी क़िफ़ायत पर (1 लीटर में 80 कि.मी.*), तो कई इसकी देखभाल के कम ख़र्च पर फ़िदा हैं। उन्हें 'होन्डा' पाने की चाह हमेशा से थी। कुछ ऐसे भी हैं जो 4-स्ट्रोक वाली भारत की एकमात्र 100 सी.सी. मोटरसाइकिल चलाने में ग़ज़ब का आनन्द पाते हैं। ये सारी देन है हीरो की सूझ-बूझ की – होन्डा इन्जिनीयरिंग चुनने की सूझ-बूझ।

2,00,000 से अधिक संतुष्ट ख़रीदार

नतीजा आपके सामने है – हीरो होन्डा अपनाने वाले 2,00,000 व्यक्ति, अपने चुनाव से हर तरह से संतुष्ट। तभी तो हम यकीनन् कह सकते हैं – यही है आपका शानदार हमसफ़र।

** 40 कि.मी. प्रति घंटा पर, 130 किलो भार सहित.*

HERO HONDA

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पायेंगे. दिल की बात कहने से.

"बड़े आराम की सवारी है – मज़बूत और टिकाऊ। और हाँ, धुआं ज़रा नहीं करती."

"ये मत पूछिए क्यों। मुझे बस यही पसन्द है – पिछले तीन सालों से."

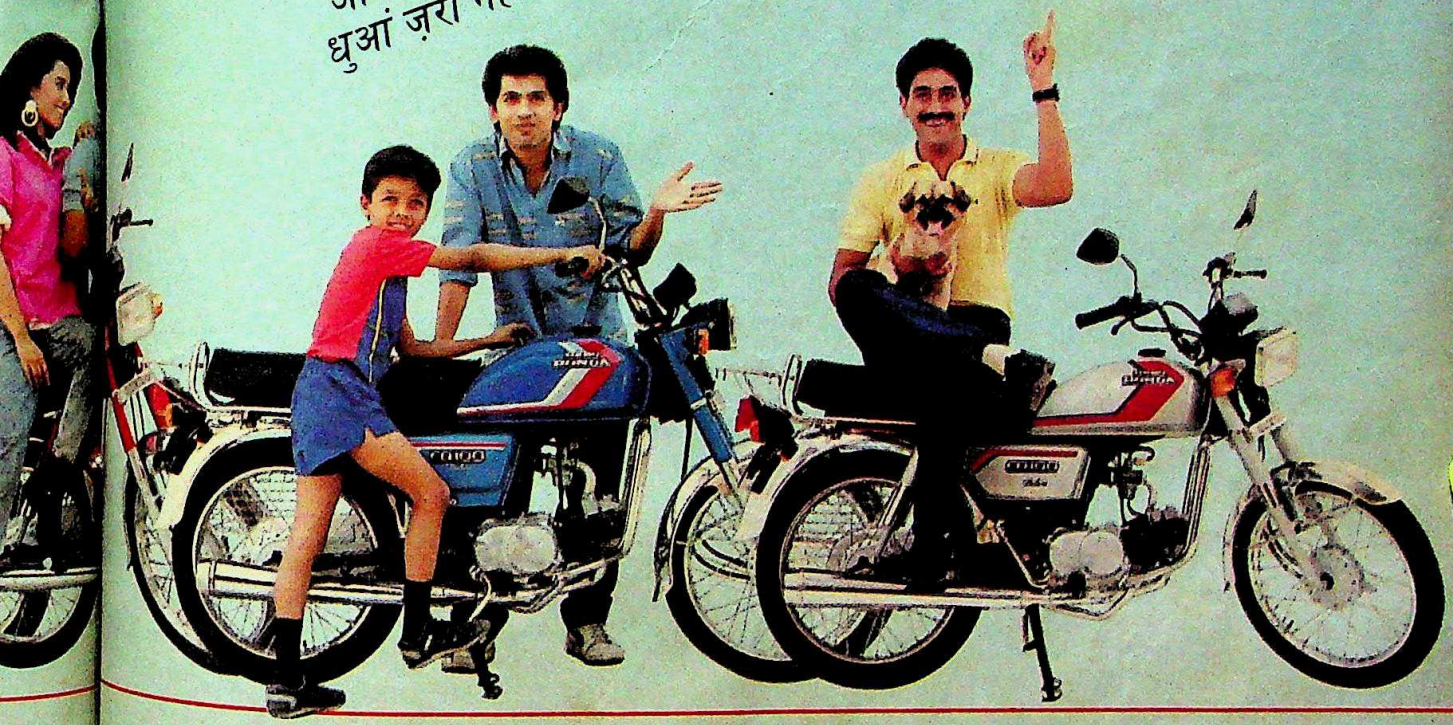

देखा आपने, सब की एक राय...

आपका शानदार हमसफ़र!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हर मौसम में
लुभावना
एकमात्र
प्रदेश

अतुलनीय सौंदर्य

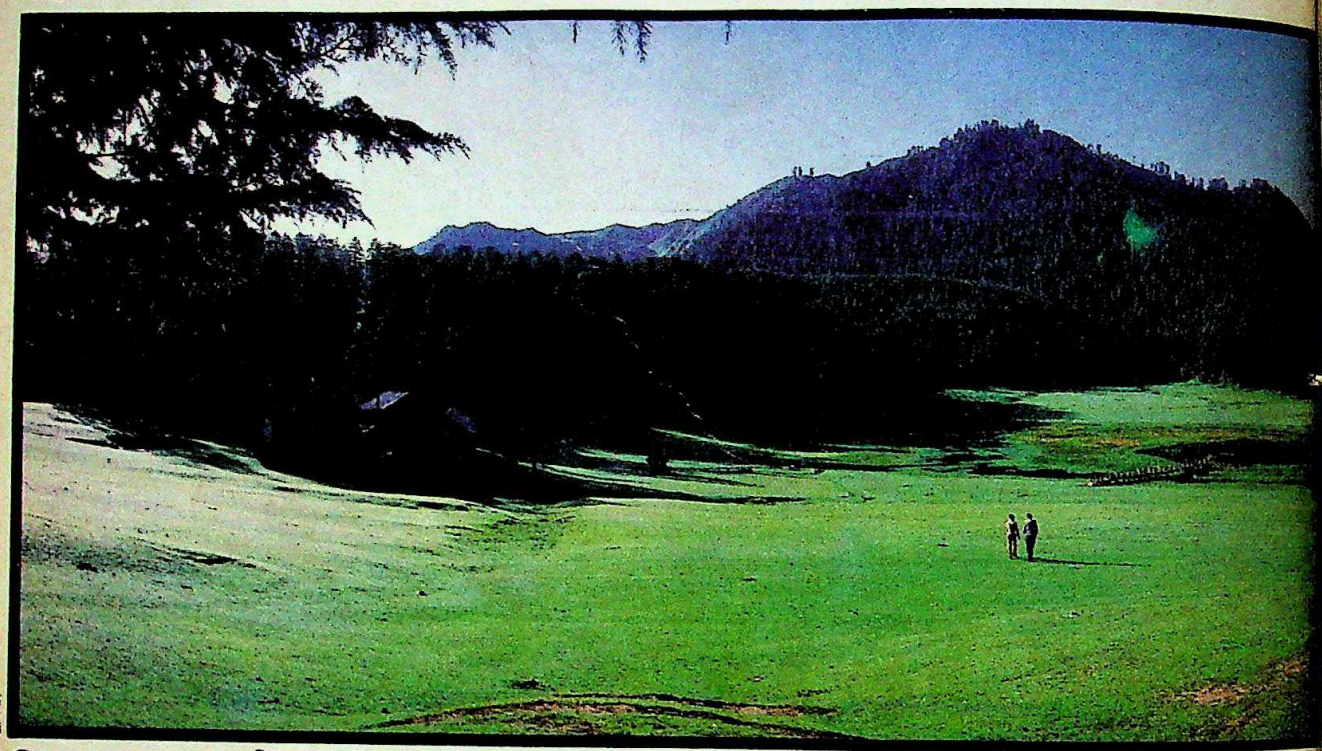

चंबा घाटी

हिमाचल प्रदेश

कदमों को चूमती मुस्कुराती कलियां, हवा की मनमोहक सुगन्ध, पक्षियों की चहक। कल्पना कीजिए... हिमाचल में घूमते हुए, एक जादुई एहसास जब आप रोमांचित हो उठें।

विविध धर्म, तरह-तरह के पर्व, फूल, फल, वृक्ष, मौसम, खेल और जाने क्या क्या।

सावन की घटा हो या बसन्त का आगमन, बर्फ की फुहार हो या पहाड़ों में गर्मियों से राहत, हर मौसम में हिमाचल का सौंदर्य निखर आता है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

HIMACHAL TOURISM
हिमाचल पर्यटन
कमिश्नर पर्यटन
हिमाचल प्रदेश
डैज़ी बैंक एस्टेट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Satish Sud Graphics

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

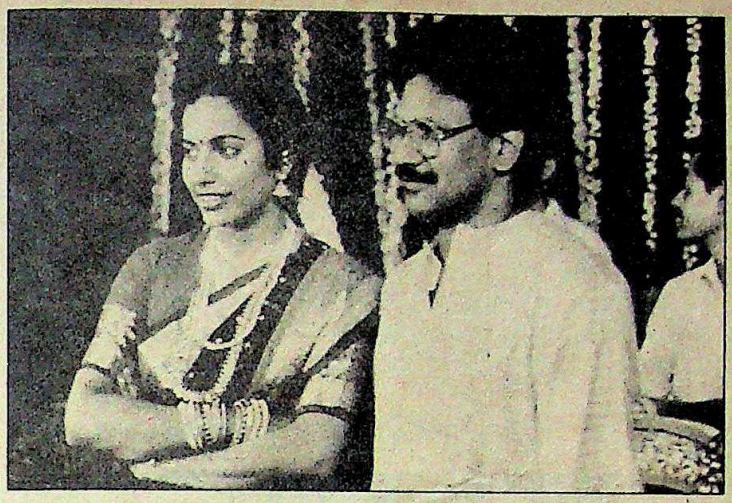

सुहासिनी-रत्नम

गांठ बंध गई

लेकिन समारोह में कई बड़े सितारे नहीं आए

यों तो फिल्मी दुनिया में और खास तौर से दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में आए दिन कोई न कोई शगूफा छूटता ही रहता है. पर पिछले दिनों विख्यात तेलुगु अभिनेत्री सुहासिनी और तमिल फिल्म निर्देशक मणिरत्नम के विवाह ने मद्रास की अफवाफूसी पनचक्की को नया मसाला उपलब्ध कराया उसके चर्चे कई दिनों देर तक गूंजते रहने वाले हैं. एक ऐसी दुनिया में जहां फिल्मी सितारों के विवाह जैसे मौके कभी-कभार ही आते हैं, मेजबान के अलावा आने वाले और न आने वाले दोनों तरह के मेहमान भी खबरों और अफवाहों का केंद्र बने बिना नहीं रहते. सुहासिनी-मणिरत्नम विवाह भी इस मायने में किसी से पीछे नहीं रहा.

जहां एक ओर दक्षिण भारतीय फिल्मी बिरादरी और इंका की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने पार्टी में शामिल होकर इस मौके को एक रंगबिरंगे फिल्मी मेले का रूप दिया वहीं दूसरी ओर कमलहासन, शिवाजी गणेशन, एम. करुणानिधि और एन.टी. रामराव जैसी हस्तियों की अनुपस्थिति ने अटकलबाजियों का बाजार गरमा दिया. खासकर कमलहासन की गैरमौजूदगी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर कुछ ज्यादा ही खींचा. वे कमलहासन ही थे जिन्होंने आठ साल पहले अपनी भतीजी सुहासिनी को फिल्मी परदे पर प्रस्तुत किया था. इसके अलावा रत्नम के साथ भी उनके रिश्ते खासे अच्छे रहे हैं. लेकिन अपनी पूर्व पत्नी वाणी गणपति के साथ वैवाहिक रिश्ता टूटने के बाद जिस तरह कमलहासन ने अपने पूरे परिवार से संबंध ठंडे किए हुए हैं उसे देखते हुए लोगों को कम ही उम्मीद थी कि वे इस विवाह में शिरकत करेंगे. पार्टी के अलावा उससे पहले दिन शादी की रस्म के समय भी वे नदारद थे जबकि दोनों दिन वाणी पूरे दमखम के साथ वहां इठलाती घूम रही थीं.

हासन के नजदीकी लोगों का कहना है कि इस दौरान वे मद्रास से बाहर अपने गांव परमाकुडी में थे जहां उनके पिता बीमार चल रहे हैं. जिन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि रत्नम के साथ अपनी दोस्ती की वजह से वे समारोहों में कुछ देर के लिए जरूर आएंगे, उन्हें खासा मायूस होना पड़ा. जब हासन की गैरमौजूदगी के बारे में रत्नम से पूछा गया तो उनका टका-सा जवाब था, "मुझ से क्या पूछते हैं कि वे क्यों नहीं आए? यह सवाल उन्हीं से पूछिए." लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हासन की गैरमौजूदगी ने दोस्ती के रिश्तों को हमेशा के लिए खट्टा कर दिया हो. इस सवाल के जवाब में कि क्या अब वे हासन के साथ फिल्मों में काम करेंगे, ठेठ व्यापारिक शैली में उनका कहना था, "क्यों नहीं? मेरी शादी में न आने और एक साथ फिल्में बनाने के बीच भला क्या ताल्लुक है. अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट हो तो हम लोग यकीनन एक साथ काम करेंगे."

न आने वालों की सूची में शिवाजी गणेशन का स्थान भी खासा महत्वपूर्ण रहा. उनके न आने का मुख्य कारण तमिलनाडु इंका अध्यक्ष जी.के. मूपनार की मौजूदगी थी जो रत्नम के भाई और दक्षिण भारतीय फिल्म चैंबर के पूर्व अध्यक्ष जी. वेंकटेश्वरन के निजी मेहमान थे. वेंकटेश्वरन इंकाई हलके में खासे लोकप्रिय हैं. खानापूर्ति करने के लिए गणेशन ने अपने अभिनेता पुत्र प्रभु को भेज दिया. उधर रामराव की ओर से यही भूमिका उनके बेटे ने भी निभाई. जहां तक आने वालों की बात है, उनमें रजनीकांत और उनकी पत्नी लता, विख्यात अभिनेता सत्यराज और विजकांत, निर्देशक टी. राजेंद्रन तथा पूर्णिमा भाग्यराज से लेकर रेखा, शरण्या तथा श्रीदेवी जैसी हस्तियां भी वहां मौजूद थीं. आने वालों में निर्देशक बालाचंदर भी थे जिनकी फिल्म 'सिंधु भैरवी' में अपनी भूमिका के लिए सुहासिनी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है.

हालांकि सुहासिनी पेशे से सिनेमाटोग्राफर हैं और 1981 में वे दक्षिण की पहली महिला सिनेमाटोग्राफर के रूप में अपनी जगह बनाने जा रही थीं लेकिन बालू महेंद्र की तमिल फिल्म 'निजातै-किल्लातै" (मेरा दिल मत दुखाओ) में हीरोइन की भूमिका स्वीकार करके उन्होंने अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया. इस फिल्म में उन्होंने पुरस्कार और शोहरत दोनों हासिल की. बाद में देखते ही देखते उन्होंने तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अच्छी खासी जगह बना ली. अब तक लगभग 60 फिल्मों में काम कर चुकीं सुहासिनी ने विवाह से ठीक दो दिन पहले तक ओवरटाइम शूटिंग करके अपनी लगभग सभी फिल्में पूरी कर डाली है. हनीमून के लिए लंदन रवाना होने से पहले भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में उनका कहना था, "ऐसा नहीं है कि मैं अभिनय से संन्यास नहीं लेने जा रही. हो सकता है भविष्य में मैं निर्देशन का काम भी करूं."

अपने भाई वेंकटेश्वरन के मुकाबले शांत रहने वाले रत्नम ने अब तक केवल पांच फिल्मों का निर्देशन किया है. दस साल पहले एमबीए पास करने के बाद अचानक फिल्मों में आ कूदे रत्नम की पहली तमिल फिल्म 'मौन रागम्' को सर्वोत्तम क्षेत्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला था और उनकी दोनों नवीनतम फिल्में 'नायकन' और 'अग्नि नक्षत्रम' टिकट खिड़की पर खासी सफल हो चुकी हैं. दोनों के चाहने वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यह जुगल जोड़ी अपनी खूबियों का साझा इस्तेमाल नई फिल्में बनाने में करेगी और सुहासिनी चूल्हे-चकले के चक्कर में नहीं जा फंसेंगी.

—ललिता दिलीप

सुहासिनी और मणिरत्नम: दो सितारों का मिलन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंदी थिएटर

विदेशी नाटकों की बैसाखी

मंचन किए जा सकने वाले मौलिक नाटकों का भारी अभाव

दिल्ली की सांस्कृतिक राजधानी मंडी-हाउस के शांत और हरे-भरे इलाके में स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रानावि). चोटी के रंगकर्मियों की इस मायानगरी के गलियारे उन नाटकों के पोस्टरों से सजे रहते हैं जिन्हें यहां के महारथी निर्देशकों और प्रशिक्षणार्थियों ने बीते बरसों के दौरान मंचित किए हैं.

पहला पोस्टर गोल्दोनी के 'द फैन' के बारे में है. दूसरे में ब्रेख्त के 'काकेशियन चाक सर्कल' के हिंदी रूपांतर 'इंसाफ का घेरा' के मंचन की घोषणा है. बाकी पोस्टरों में भी 'तलघर' (लोअर-डेप्थ्स: मैक्सिम गोर्की), 'नौकर शैतान, मालिक हैरान' (द सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स: गोल्दोनी), और 'चोपड़ा कमाल, नौकर जमाल' (पुंटीला ऐंड हिज मैन माट्टी: ब्रेख्त) जैसे विदेशी मूल के नाटकों की भरमार है. कुछेक पोस्टरों में गिरीश कर्नाड के 'तुगलक' और रसिकलाल पारीख के 'मीना गुर्जरी' जैसे गैर-हिंदी भारतीय नाटक भी सिर उठाए दिखते हैं. पोस्टरों की कतार में कहीं-कहीं धर्मवीर भारती के 'अंधा युग' और त्रिपुरारी शर्मा के 'काठ की गाड़ी' जैसे नाटक यह आधा-अधूरा एहसास दिलाने की कोशिश जरूर करते दिखते हैं कि हिंदी में भी मंचन योग्य नाटक लिखे जा सकते हैं.

इन्हें देखने के बाद रानावि में आने वाला मेहमान इस सवालिया हैरानी के साथ बाहर निकलता है कि क्या हिंदी में नाटक लेखन सचमुच दिवालिया हो चुका है? रानावि से बाहर खेले जाने वाले नाटकों की सूची में भी मोलियर, इब्सन, बायखनर शेक्सपीयर और आर्थर मिलर जैसे नामों की भरमार देखने को मिलती है.

देश के हिंदी रंगमंच का सबसे सक्रिय स्थान माने जाने वाले श्रीराम केंद्र में इस साल अब तक जो 87 नाटक खेले गए हैं, उनमें से आधे से अधिक नाटक दूसरी भाषाओं से लिए गए उधार खाते के हैं. दूसरे शहरों-कस्बों की नाटक मंडलियां भी 'आधे-अधूरे', 'अंधा युग', 'महाभोज', 'मशरिकी हूर' और 'आषाढ़ का एक दिन' जैसे पुराने नाटक खेलकर ही खानापूरी करती दिखती हैं.

आजकल एक साल में जितने नाटकों का प्रकाशन होता है उनकी संख्या पिछले दस साल के दौरान मंचित हुए कुल नाटकों से भी अधिक होती है. लेकिन ऊंचे दामों पर प्रकाशित इन नाटकों में से ऐसे नाटकों की संख्या उंगलियों पर भी गिने जाने के काबिल नहीं है जिन्हें निर्देशकों ने मंचन योग्य पाया हो या जिनका मंचन हुआ हो.

किताबों की इस बाढ़ के बारे में विख्यात हिंदी रंगकर्मी और रानावि रंगमंडल के पूर्व अध्यक्ष जे.एन. कौशल कहते हैं, "प्रकाशक की बिरादरी इन किताबों का प्रकाशन रंगमंच के लिए नहीं बल्कि सरकारी लाइब्रेरियों द्वारा एकमुश्त खरीद के लिए कर रही है. उनका छपना या न छपना रंगमंच के लिए कोई मतलब नहीं रखता."

हिंदी नाटक निर्देशक की यह हताशा बहुत बेमानी भी नहीं है. पिछले तीन चार दशकों में किए गए हिंदी नाट्य लेखन और मंचन पर निगाह दौड़ाते ही जो बात सबसे पहले चौंकाती है वह यह है कि 60-70 वाले दौर में आया उभार अब ठंडा पड़ चुका है. मोहन राकेश (आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे-अधूरे), सुरेंद्र वर्मा (एक दूनी एक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी) और डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल (आवारा अब्दुल्ला, पंछी अंधा, कुआ, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, मि. अभिमन्यु, शगुन) की तिकड़ी और धर्मवीर भारती (अंधा युग), के बाद सिवाय कुछ इक्का-दुक्का अच्छे नाटकों के नाटककारों की कोई नई परंपरा दिखने में नहीं आ रही. अकेले-दुकेले प्रयासों में से प्रभावशाली नाटकों की संख्या भी उंगलियों पर गिनने लायक ही है. इस वर्ग में भीष्म साहनी (हानूश, कबिरा खड़ा बाजार में), हबीब

'कुमार स्वामी': प्रतिभा ढूंढ़ने से मिलेगी

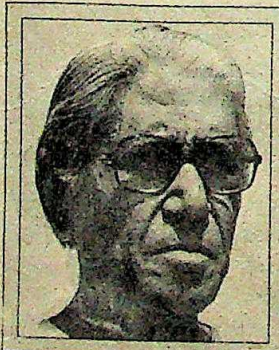

रामकिशोर पारचा

"नए नाटकों पर कोशिश करने के बजाय निर्देशक दूसरी भाषाओं के नाटकों पर निर्भर रहना चाहते हैं"

नेमिचंद्र जैन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चोर (चरणदास चोर), शंकर शेष (एक द्रोणाचार्य, पोस्टर), असगर वजाहत ना की आवाज), त्रिपुरारी शर्मा (काठ गाड़ी, बांझ घाटी, बहू), सर्वेश्वर दयाल ना (बकरी, लड़ाई), मृणाल पांडे (चोर न के भागा) और सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ तीला) जैसे नाम ही प्रमुख हैं. मूल के अलावा आशा की एक किरण कुछ उपन्यासों के नाट्य रूपांतरों के रूप में मकी है पर फिलहाल यह गिने-चुने तक ही सीमित है. इस वर्ग में मन्नू का 'महाभोज,' कृष्णा सोबती का रजानी', श्रीलाल शुक्ल का

अपनी भाषा में अच्छा नाटक नहीं है तो दूसरी भाषा का अच्छा नाटक लेने में बुराई ही क्या है? असली मतलब तो दर्शक के सामने एक अच्छी चीज पेश करना है."

जहां तक नाटक लेखन के आर्थिक पहलू की बात है, पूरे हिंदी रंगमंच की हालत 'खस्ता' से बेहतर नहीं कही जा सकती. हालत यह है कि टिकटों की बिक्री से अगर हॉल, फर्नीचर और पोशाकों का किराया भी निकल आए तो नाटक को 'सफल' मान लिया जाता है. ऐसे में नाटककार को रायल्टी देने

'विटनेस फॉर द प्रासीक्यूशन': उधार खाता

भी जाती है वहां भी प्रति मंचन 100 रुपए से अधिक नहीं दिया जाता. ऐसा शायद ही कभी होता होगा कि कोई नाटक मंडली किसी नाटक के तीन या चार से ज्यादा शो करे. मराठी और बंगला रंगमंच से हिंदी की तुलना करते हुए कौशल बताते हैं, "वहां तो फ्लॉप होते-होते भी नाटक के 50 शो हो जाते हैं और नाटककार को 200 रुपए प्रति शो के हिसाब से 10 हजार रुपए मिल जाते हैं."

हिंदी रंगमंच के लिए लेखन की मौजूदा हालत के बारे में जाने-माने रंग समीक्षक नेमिचंद्र जैन का कहना है कि हालत उतनी खराब नहीं है जितना शोर मचाया जा रहा है. इसके लिए काफी हद तक निर्देशकों को दोषी ठहराते हुए वे कहते हैं कि नए नाटकों पर कोशिश करने के बजाय निर्देशक दूसरी भाषाओं के जमे-जमाए नाटकों के रूपांतरों पर निर्भर रहना चाहते हैं.

नए नाटक लिखने और उनके मंचन की दिशा में इधर पिछले पांच साल में कुछ ऐसे प्रयास भी हुए हैं जिनसे आशा की जा सकती है कि मौजूदा जड़ता की गांठें ढीली होंगी. संगीत नाटक अकादमी ने नाटक की लोक तथा परंपरागत शैलियों के प्रति युवा रंगकर्मियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग देने तथा इस तरह से तैयार किए गए नाटकों के क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर समारोह आयोजित करने की योजना शुरू की है. इसी तरह दिल्ली प्रशासन की साहित्य कला परिषद पिछले चार साल से राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, पंजाबी और उर्दू नाटक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है. परिषद के सचिव सुरेंद्र माथुर बताते हैं कि हर साल लगभग 300 नए हिंदी नाटककार इसमें भाग ले रहे हैं और इनमें से कम-से-कम 20 नाटक ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़े-बहुत परिवर्तन के बाद मंचित किया जा सकता है. परिषद अपने युवा महोत्सव में इनमें से छह नाटक मंचित भी कर चुकी है. इनमें से कुमार स्वामी (नवनीद्र बहल), झूठ-पुराण (विनोद साही) और युयुत्सु (राजेश शर्मा) को काफी सराहा गया था. देखना यह है कि आर्थिक दबावों और विदेशी नाटकों के तिलस्मी दुष्चक्र में फंसा हिंदी रंगमंच कब और कैसे आत्मविश्वास की राह पकड़ता है.

—विजय क्रान्ति

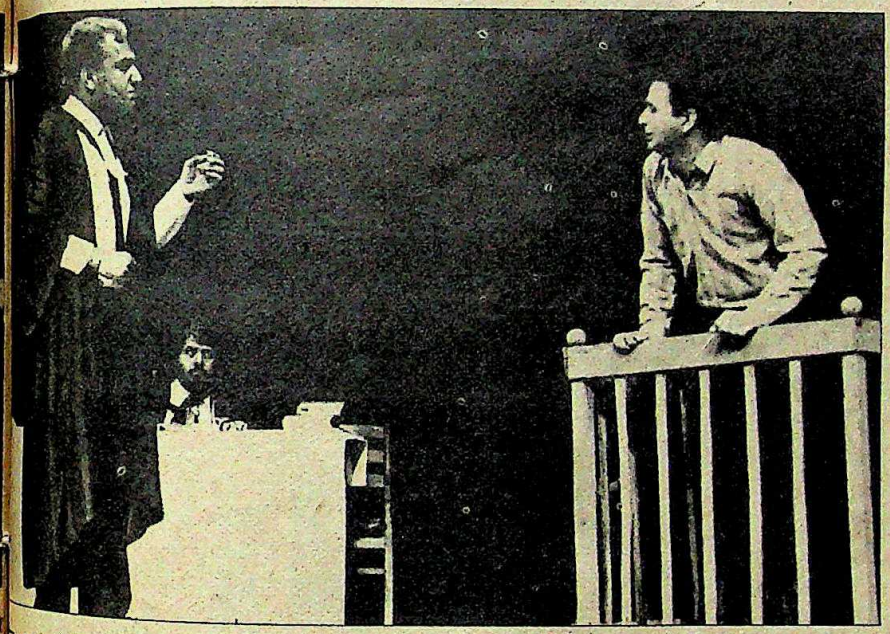

दरबारी' और पं. आनंद का 'बेगम का तकिया' जैसे गिनाए जाने लायक हैं.

गीत नाटक अकादमी में सह (नाटक) भारतरत्न भार्गव न पर गैर-हिंदी नाटकों के के लिए काफी हद तक लेखक ही दोषी मानते हैं. उनके ार, "हिंदी नाटककार न केवल ने में कटा हुआ है बल्कि वह क के साथ बैठकर मंच की स्थितियों के अनुसार लिखने के भी तैयार नहीं है. नतीजा यह होता है निर्देशक तैयारशुदा गैर-हिंदी नाटकों को अपनाने में फायदा देखता है."

गैर-हिंदी नाटकों की ओर निर्देशकों के ने को उचित ठहराते हुए जाने-माने क बृजमोहन शाह कहते हैं, "नाटक ौलिक होता है. वह भाषा और देश के र में बांधी जाने वाली चीज नहीं है. अगर

"नाटक तो भाषा और देश की सीमाओं से बाहर की चीज है. दूसरी भाषा का अच्छा नाटक लेने में बुराई क्या है?"

बृजमोहन शाह

राम किशोर पारचा

की परंपरा अगर हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में नहीं बन पाई तो किसे हैरानी होगी? कई नाटकों के लेखक शाह शिकायत भरे अंदाज में कहते हैं, "मेरे नाटकों के मंचन के लिए रायल्टी भेजने की बात तो छोड़िए, नाटक करने वाले लोग पोस्टकार्ड लिखकर इसकी सूचना देने की तकलीफ भी नहीं गवारा करते."

जिन मामलों में नाटककार को रायल्टी दी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत: एक खोज

इतिहास की वीथिकाओं में

कुरुक्षेत्र का मैदान. महाभारत समाप्त हो गया है और चारों तरफ मुंडी-तुड़ी गदाएं और खून से लथपथ ढालें बिखरी पड़ी हैं. मुर्दनी छाई हुई है. इस वीराने में जवाहरलाल नेहरू की छवि उभरती है. वे चकित नजर आते हैं. उनकी पेशावरी चप्पल युद्ध का मलबा रौंद रही है. एकाएक वे मुड़ते हैं, तनकर खड़े होते हैं और महाभारत के सबक पर भाषण देने लगते हैं.

एक और युद्धभूमि का एक कोना. यहां रावण धराशायी है. खिन्न तथा दुविधाग्रस्त राम और अनिच्छुक लक्ष्मण ब्राह्मण दशग्रीव के पास राजनीति के गुर सीखने पहुंच रहे हैं.

दूसरे दिन सुबह अपने भयावह चेहरे पर मृत्यु का संदेश लिए स्थूलकाय यमदेव सल्फर से बने धुएं का आवरण चीरते अवतरित होते हैं. वे युवा नचिकेता को उपनिषदों पर पाठ सुनाते हैं. फिर रातोरात कुरुक्षेत्र बीहड़ में बदल जाता है.

श्याम बेनेगल का पूरे दिन का काम है यह. भारत के गैरसरकारी सिनेमाई फनकार बेनेगल ने जवाहरलाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पर आधारित 52 भागों के टीवी धारावाहिक के निर्माण के लिए इस महाकाव्यात्मक पृष्ठभूमि की रचना की है. इस धारावाहिक का प्रसारण नवंबर में नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू होगा. 'भारत : एक खोज' नामक दूरदर्शन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर राजकोष से 4 करोड़ रु. से कहीं अधिक रकम खर्च हो सकती है. भारत में इतने बड़े पैमाने पर किसी धारावाहिक का निर्माण नहीं हुआ.

बेनेगल भी खर्च में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं. मौर्य, गुप्त और चोल वंश की राजधानियों के भव्य दृश्य बंबई के फिल्म सिटी स्टुडियो में सब तरफ बने दिखते हैं. इनमें प्राचीन नगरों के बारीक-से-बारीक ब्यौरों का ध्यान रखा गया है. अशोक काल के दृश्यों के निर्माण में कम-से-कम 15 लाख रु. का खर्च आएगा. वस्त्र-आभूषणों का जिम्मा संभाल रही शमा जैदी उनको वास्तविक रंग देने की भरसक कोशिश कर रही हैं. यहां तक कि खड़ाऊं भी लोकेशन पर बने एक छोटे कारखाने में बनाए जा रहे हैं.

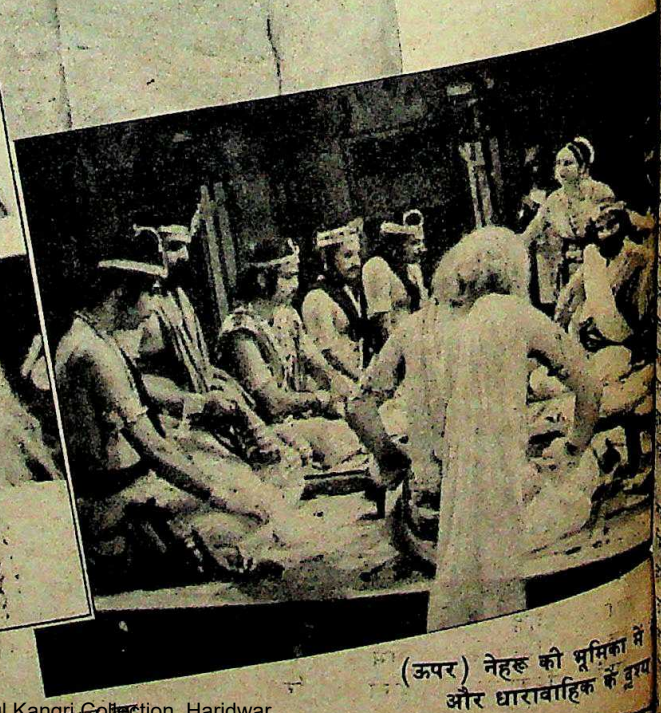

(ऊपर) नेहरू की भूमिका में और धारावाहिक के दृश्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्याम बेनेगल

नेहरू की नजर से

*श्याम बेनेगल हर मौके पर नेहरूवाद पर जरूर बोलते हैं और अतीत का हवाला देते हैं. अपने नए दूरदर्शन धारावाहिक में, जिस पर वे 1984 से काम कर रहे हैं, उन्होंने देश की मौजूदा असंख्य और जटिल समस्याओं को नेहरू के नजरिये से देखने की कोशिश की है. प्रमुख संवाददाता **मधु जैन** ने बंबई में फिल्म के सेट पर उनसे बातचीत की. उसी के अंश:*

• आज नेहरू की प्रासंगिकता पर:

नेहरू संकट को पहले ही भांप सकते थे. उन्होंने लोगों की हिस्सेदारी के बिना उभरने वाले राष्ट्रीयतावाद के संकट की चेतावनी दी थी. वे इस बात में भरोसा करते थे कि चीजें राज्य की होनी चाहिए लेकिन वे राज्यवाद के खिलाफ थे. पर उनके बाद राज्यवाद हावी हो गया. हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत को भी देख रहे हैं. यही नेहरू की दृष्टि थी.

• धर्मनिरपेक्षता पर:

'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में नेहरू भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं पर विचार करते हैं. राष्ट्र अपने आप में एक नई अवधारणा है, हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं. लेकिन धर्मनिरपेक्षता कोई नई प्रक्रिया नहीं है. और हम इन सब चीजों को इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. अफगान आए, तुर्क-अफगान आए और अरबी आए. वे इस देश में रच-बस गए. लेकिन अंग्रेज यहां की माटी में रचे-बसे नहीं. धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारत के इतिहास के हर काल में मिलती है.

• फिल्म क्या संदेश देती है:

आखिरी किस्त में हम सवाल करते हैं कि हम किधर बढ़ रहे हैं. हम जानते हैं कि हम प्रगति और विकास की सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं. सामने रुकावटें आने पर हमें अधबीच ही गलती सुधारनी होगी. लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें गलती सुधारी जा सकती है.

• रामायण और महाभारत को धारावाहिक में क्यों शामिल किया गया:

भारतीयों का जीवन सामाजिक और नैतिक मान्यताओं पर आधारित होता है. इन दोनों महाकाव्यों में ये चीजें मिलती हैं. हम इन दोनों महाकाव्यों और चाणक्य के अर्थशास्त्र को महत्व दे रहे हैं. चाणक्य केंद्रीकरण के कट्टर हिमायती थे. हम महाकाव्यों को धार्मिक नजरिये से नहीं बल्कि उनके ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व की दृष्टि से देखते हैं. अगर हमें धर्म से मिसाल लेनी हो तो हमें नागरिक मिसाल चुननी चाहिए और उसमें से धर्म का भाव हटा देना चाहिए.

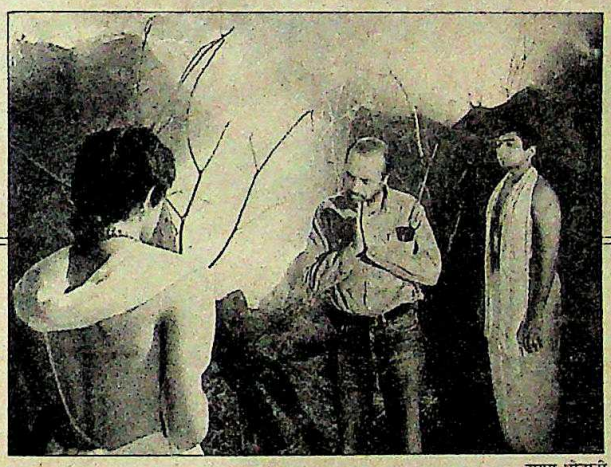

नामस भोजानी

नेहरू की महान कृति का फिल्मांकन सुविधाजनक है. यह पुस्तक [illegible] को इतिहास और यहां तक [illegible] प्राग्-इतिहास की उनकी यात्रा [illegible] 5500 वर्षों (ई. पूर्व 3500 [illegible] प्राग्-सिंधु घाटी सभ्यता से [illegible] 1946 तक) के काल की [illegible]कात करने का अवसर प्रदान करती है. [illegible] कालखंड के चित्रण में बेनेगल कल्पना का [illegible] उपयोग कर सकते हैं. वे धर्मग्रंथों, [illegible] और भारत के सामूहिक अवचेतन [illegible] के पौराणिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में [illegible] विस्तार से विचरण कर सकते हैं. नेहरू ने [illegible] सबका बहुत विस्तार से वर्णन किया है. [illegible] बताते हैं, "हमने नेहरू दर्शन के मूल [illegible] को पकड़ने की कोशिश की है. हमने [illegible]तीय इतिहास की प्रक्रिया और उन [illegible]नाओं पर दृष्टिपात किया है जिनसे होकर [illegible] आज इस स्थिति में पहुंचे हैं. आज इस [illegible]कात की सबसे ज्यादा जरूरत है."

बेनेगल को टीवी धारावाहिक के लिए [illegible] से बेहतर शायद कोई किरदार नहीं [illegible] सकता था. इस किरदार की आवाज में [illegible]-सी नाक से बोलने की ध्वनि है लेकिन [illegible]चारण विशुद्ध हिंदुस्तानी है. रोशन सेठ ने [illegible] की भूमिका बखूबी निभाई है. उनके [illegible] यह भूमिका जानी-पहचानी है. वे रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 'गांधी' में नेहरू की भूमिका कर चुके हैं. वे कहते हैं, "मुझे नेहरू की भूमिका में उतारकर श्याम ने समझदारी का परिचय दिया. चूंकि मैं यह भूमिका पहले कर चुका हूं इसलिए लोगों को यह स्वीकार्य होगा. नेहरू अंग्रेजी में सोचते थे, इसलिए नेहरू के चरित्र को एकमात्र उसी भाषा के जरिये मैं संप्रेषित कर सकता हूं."

अपनी पहली भूमिका की तरह इस बार वे इतिहास की घटनाओं का एक हिस्सा नहीं बनते बल्कि वे सीधे उनमें प्रवेश करते हैं.

बेनेगल के पास दूसरे प्रभावशाली अभिनेता भी हैं. इनमें से कई तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभिनेता हैं. ओम पुरी तो इतिहास की लंबी राह में कई रूप धारण करते हैं. मसलन वे अशोक, रावण और दुर्योधन की भूमिकाएं निभाते हैं. वे अपनी खनकदार आवाज में इतिहास के अलग-अलग कालखंडों में सूत्रधार की भूमिका भी निभाते हैं. बेनेगल बताते हैं, "सूत्रधार नेहरू से अलग कोई व्यक्ति होना चाहिए. वह इतिहास के तथ्यों को एक-एक कर रखता है." ओम पुरी ने फिल्मी दुनिया से साल भर की छुट्टी ले रखी है. इस मंडली में के.के. रैना, इला अरुण, अंजन श्रीवास्तव (आर.के. लक्ष्मण के वागले, बेहतरीन अभिनेता), अनंग देसाई, विजय कश्यप और अपराजिता कृष्ण भी हैं. इनके अलावा नाटककार सत्यदेव दुबे चतुर चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं.

बेनेगल जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं उसके लिए नेहरू की किताब बढ़िया आधार साबित हो रही है. इसमें वे तथ्यों और कल्पना से रचे-पगे इतिहास के नाट्य रूप, दस्तावेजी टिप्पणियां, छऊ नृत्य, वैदिक ऋचाएं, हाल के कुछ नाटक और व्यंग्य-रचनाएं सब कुछ भर देते हैं. यहां तक कि बेनेगल तथा नेहरू की भूमिका कर रहे सेठ बौद्ध धर्म की खोज में अंगकोर वाट, तक्षशिला, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका का भी सफर करते दिखते हैं. दस्तावेजी टिप्पणियां भी फिल्म के बीच-बीच में चलती रहती हैं.

मौर्य और गुप्त काल का फिल्मांकन हो गया है. बेनेगल फिलहाल मोहनजोदड़ो पर किसी शोध छात्र की तरह अपना ध्यान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नितीश राय

कल्पना कंक्रीट में

फंतासियों के इस चितेरे का जवाब नहीं. 35 वर्षीय, ठिगने, विनम्र और शर्मीली मुस्कान वाले नितीश राय बंबई फिल्मोद्योग में अपनी जगह बना चुके हैं. वे कल्पनाओं को कंक्रीट में बदलते हैं. इस युवा कला निर्देशक ने ढिशुम-ढिशुम वाली फिल्मों में बदमाशों के अड्डे बनाने से लेकर 'भारत: एक खोज' के लिए भव्य सेट्स तैयार किए हैं.

इस परियोजना में वे लगभग 200 लोगों का कामकाज देख रहे हैं. राय का कैरियर शुरू हुआ 1981 में. जिस समय वे कलकत्ता में ललित कला महाविद्यालय में छात्र थे तो मृणाल सेन की नजर उन पर पड़ी. उन्होंने 'खंडहर', 'खारिज' और 'जेनेसिस' फिल्मों के सेट बनाए. फिर बेनेगल उन्हें 'मंडी' फिल्म के लिए बंबई ले गए. 'मंडी' के बाद उन्हें 'त्रिकाल' और 'सुस्मान' के लिए काम करना था. इसी बीच, बंबइया मसाला फिल्म निर्माताओं के अलावा गोविंद निहलाणी (आघात, पार्टी और तमस) और रमेश शर्मा (न्यू दिल्ली टाइम्स) ने भी उनसे अपनी फिल्मों के लिए काम करवाया.

राय के लिए 'भारत: एक खोज' सबसे बड़ी चुनौती है. राय कहते हैं, "मैं हमेशा विस्तार से काम करता हूं. लोग मुझे खर्चीला कहते हैं. लेकिन मैं कर क्या सकता हूं? हर स्तंभ पर इतिहास की छाप होनी चाहिए." सबसे ज्यादा मुश्किल काम इतिहास के उन कालों की पुनर्सर्जना थी जो दर्ज नहीं हैं और जिनकी शिल्पकृतियां मौजूद नहीं हैं. मिसाल के तौर पर, मौर्य काल के शायद ही कोई अवशेष मिलते हैं क्योंकि उस समय लकड़ी के ही घर आदि बनाए जाते थे. लिहाजा, लगभग तीन साल तक किताबों का अध्ययन करना पड़ा और संग्रहालयों तथा दूसरी जगहों से सांची के स्तंभों, प्रस्तर कलाकृतियों और दूसरी शिल्पकृतियों के चित्र लेने पड़े. "मैंने भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआई) के एम.सी. जोशी के साथ एक काल के बाद दूसरे काल का अध्ययन किया."

राय ने अपने ज्यादातर रंग संयोजन जातक भित्ति-चित्रों से लिए हैं. उनके द्वारा बनाए गए अधिकतर राज्यों में जातक भित्ति-चित्रों वाले मनभावन गेरुए, रेड-ऑक्साइड, तांबई और नीले रंगों का इस्तेमाल हुआ है. उनका काम उस समय और भी आसान हो गया जब इस्लामी दौर शुरू हुआ.

दुर्भाग्य की बात यह है कि गुप्त, संगम और मौर्य काल ज्यादा भ्रामक साबित हुए हैं. राय की शिकायत है, "किसी ने उन कालों के पुनर्सर्जन की कोशिश नहीं की." और जिन्होंने की भी, तो बहुत ही सतही तरीके से की. लिहाजा, राय को सबसे पहले इतिहास के उन कालों के गलत-सलत शिल्प की तहों से बाहर निकलना पड़ा जिन्हें फिल्म निर्माताओं ने रचा था. विडंबना तो यह है कि राय के काम में भव्य मिथक फिल्में बड़ी बाधाएं हैं. राय शिकायत करते हैं, "यह तीसरे दर्जे की कैलेंडर कला है. नक्काशी और स्तंभों का गलत इस्तेमाल किया गया है. ऐतिहासिक घटनाओं पर फिल्म बनाने वाले अधिकतर फिल्म निर्माताओं ने रवि वर्मा की कलाकृतियों का अनुकरण किया है. ये कलाकृतियां 19वीं शताब्दी की शैली में बनी हैं और इन पर तब के परिवेश की छाप है."

शायद 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' के बाद स्वप्नलोक पर मंडराने वाला रवि वर्मा का भूत दफन हो जाएगा.

—मधु जैन, बंबई में

नितीश राय: करामात

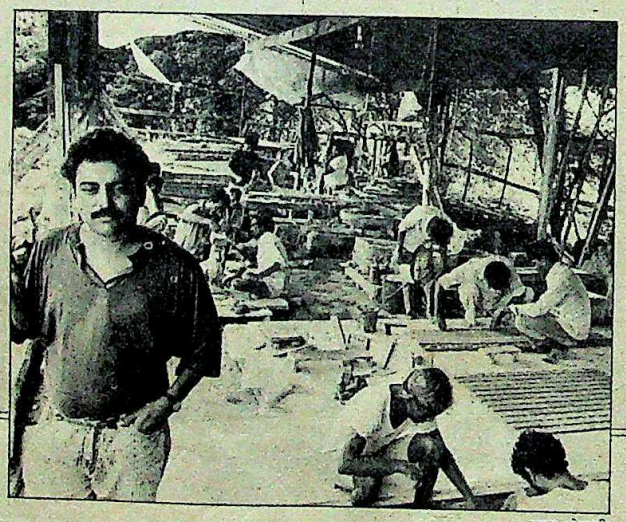

नामस भोजानी

केंद्रित किए हैं. शमा जैदी की अगुआई में पटकथा लेखकों का छोटा दल उनके जिस दफ्तर में बैठता है, वहां करीब दस हजार पुस्तकें भरी पड़ी हैं. पटकथा तैयार होने के बाद इतिहास के विभिन्न कालों के विशेषज्ञों के पास भेजी गई. इस टीवी धारावाहिक में योगदान करने वाले कुछ विद्वानों में पुणे के ए.डी. सांकलिया, अलीगढ़ के इरफान हबीब, दिल्ली विश्वविद्यालय के आर.एस. शर्मा तथा एस.आर. भट्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की चंपक लक्ष्मी और प्रोफेसर एस.ए. डांगे हैं.

भारत के अतीत और वर्तमान की यह महती यात्रा संभव है पंडिताऊ और बोझिल भी हो जाए. बेनेगल खुद बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं. निर्धारित कार्यक्रम से 10 महीने बाद फिल्मांकन शुरू करने के कारण वे अब हर दिन 10 मिनट तक दिखाए जाने लायक फिल्म बनाने को विवश हैं. बेनेगल एक तरह से इतिहास का पाठ तैयार कर रहे हैं. यह उन अभिभावकों के लिए बहुत उपयोगी होगा जिन्हें अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए उबाऊ और आम तौर पर भ्रामक पाठ्य-पुस्तकों से जूझना पड़ता है. राष्ट्रीयता और भारत की सर्वव्यापी भावना की नेहरू की भावप्रवण खोज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है. बेनेगल ने इसे फिल्म में बखूबी संप्रेषित करने की भी कोशिश की है.

वैसे, इन दिनों फिल्म सिटी में अतीत की समीक्षा का काम जोरशोर से होता दिखता है. एक दूसरे स्टुडियो में बी.आर. चोपड़ा का 'महाभारत' हो रहा है. जिसमें भगवान कृष्ण सागर में एक बहुमुखी नाग के सिर पर नाचते हैं. लेकिन यहीं दिखता है कि समुद्र के नाम पर एक छोटा-सा डबरा है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने नाग के सिर पर एक लड़की नाच रही है. इससे खस्ताहाल तकनीक का ही परिचय मिलता है. जैसा कि अभिनेत्री इला अरुणा कहती हैं, "मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इस युग में एकाएक हम रामायण और महाभारत काल में पहुंचने की सोचेंगे. मैं तो कलियुग के बारे में ही सुनती आई हूं. और अब हम मध्यकाल में लौटने लगे हैं." समय तेजी से बदल रहा है.

—मधु जैन, बंबई में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नेह संकलन

सदाबहार प्रासंगिकता

राहुल सांकृत्यायन के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात

राहुल स्मृति
संपा: रामशरण 'मुंशी', श्रीमती पुष्पलता जैन
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
दीनदयाल मार्ग, नई दिल्ली
कीमत: 60.00 रु.

राहुल स्मृति

उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में जन्मे केदारनाथ पांडे का इस बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में आकर महापंडित राहुल सांकृत्यायन के रूप में उभरना और देखते-देखते साहित्य जगत [illegible] या जाना अपने आप में समय को काफी [illegible] प्रकेलने वाली घटना थी. उनकी मेधा [illegible] वह अपूर्व शक्ति और वे तमाम गुण मौजूद [illegible] जो किसी के व्यक्तित्व को सहज ही [illegible] बहुआयामी महिमा से मंडित करते हैं. चौथे, [illegible] पांचवें और छठे दशकों के दौरान इनकी [illegible] किताबें अगर तरुण पीढ़ी बड़े चाव [illegible] से पढ़ा करती थी तो इसकी खास [illegible] वजह थी. वे किताबें उन तरुणों को [illegible] झकझोरती और आंदोलित ही नहीं [illegible] करती थीं बल्कि 'भागो नहीं, [illegible] दुनिया को बदलो' का आह्वान भी [illegible] करती थीं. बीसवीं सदी में खड़े [illegible] होकर बाईसवीं सदी की बात करने [illegible] वाले इस महान लेखक की रचनाओं [illegible] में उस दौर की तरुण पीढ़ी को [illegible] अपना भविष्य दिखाई देता था और [illegible] शायद इसीलिए उन दिनों तरुणों के [illegible] हाथों में होती थीं—'वोल्गा से गंगा', 'विश्व [illegible] की रूपरेखा', 'मानव समाज', 'दर्शन [illegible] दिग्दर्शन' या 'मेरी जीवन यात्रा' जैसी [illegible] राहुल जी की बहुचर्चित किताबें.

देश-विदेश की लगातार यात्राओं की [illegible] अटूट शृंखला वाली जीवन-यात्रा की तरह [illegible] ही घुमक्कड़राज राहुल सांकृत्यायन की [illegible] जीवन-यात्रा भी विस्तार और विविधता में [illegible] चमत्कृत कर देने वाली है. इतिहास, [illegible] पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान, भाषाशास्त्र आदि [illegible] अनेक विषय एक छोर पर, तो दूसरे छोर पर [illegible] दिखाई पड़ते हैं उनके यात्रा-वृत्तांत, उपन्यास, कहानियां, जीवनियां और राजनैतिक-सामाजिक संदर्भों को छूते चलने वाले ग्रंथ. कौन-सा था ऐसा विषय, कौन-सी थी ऐसी दिशा जिसे उनकी लेखनी ने स्पर्श नहीं किया! राहुल जी के ओझल हो जाने बाद से लेकर अब तक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है लेकिन जिस रचनाकार ने हमेशा अपने समय से आगे ही देखने वाली जीवन-दृष्टि पाई हो उसकी प्रासंगिकता यों ही खत्म नहीं हो जाती, काफी लंबी अवधि तक वह समय के साथ होती है. शायद यही वह बात है जो 'राहुल स्मृति' जैसी किताब के सामने आ जाने पर सहसा मन में उभरती है.

पुस्तक-शीर्षक 'राहुल स्मृति' से पहली बार यही लगता है कि इसमें संस्मरण ही संस्मरण होंगे लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं. संस्मरण इसमें हैं अवश्य और काफी हैं, मगर ऐसे भी कई लेख इसमें हैं जिनमें राहुल जी की भाषा और साहित्य के अनेक पहलुओं पर रोशनी डाली गई है या कुछ हद तक उनके मूल्यांकन का प्रयास किया गया है. डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया का 'भाषा अध्ययन के क्षेत्र में राहुल जी की देन' और डॉ. श्यामसुंदर घोष का 'महापंडित राहुल सांकृत्यायन के लेखन में विविधता' जैसे लेख इसी कोटि के हैं. जहां तक संस्मरणात्मक लेखों का सवाल है, वे राहुल जी के निराले व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करते हैं. संस्मरण लिखने वालों में जाने-माने रचनाकार और अपने-अपने क्षेत्र के सुस्थापित विद्वान हैं तो राजनैतिक-सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े साधारण-असाधारण लोग भी हैं. एक तरफ बाबा पृथ्वी सिंह 'आजाद' और वियोगी हरि जैसी हस्तियों के तो दूसरी तरफ भदंत आनंद कौसल्यायन, भिक्षु जगदीश कश्यप, नागार्जुन, प्रभाकर माचवे जैसे अंतरंगों के संस्मरण इसमें शामिल हैं. पत्नी कमला और पुत्री जया के संस्मरण भी इसमें हैं. जाहिर है लेखन शैली और स्तरीयता के लिहाज से इनमें काफी अलगाव या दूरियां हैं.

> **"...आचार्यों की कृतियों को तिब्बती लामाओं की अंध कंदराओं से लाकर भारतीय वाङ्मय का भंडार भरने... हिंदी जगत को समृद्ध करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन को यह हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है"**
>
> भूमिका से

आरंभ में पुस्तक का परिचय देते हुए कहा गया है कि इसमें ताजे लिखे लेख भी हैं और पूर्व-प्रकाशित लेख भी, मगर कौन-सा लेख कब लिखा गया या पहले कहीं छपा तो कब और कहां, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है. क्या यह जरूरी नहीं था? या क्या यह जरूरी काम इतना मुश्किल था कि इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया? इस पुस्तक में तो ऐसे भी संस्मरण हैं जिनके लेखक अब नहीं हैं.

'राहुल स्मृति' के साथ एक खास बात यह है कि 54 हिंदी लेखों के अलावा इसमें छह अंग्रेजी लेख भी हैं जिनके लेखकों में ए. प्लेश्कोव, मुल्कराज आनंद और के.पी. जायसवाल जैसे नाम उल्लेखनीय हैं.

मौजूदा संदर्भ में जरूरी है कि राहुल जी को याद किया जाए, उनके कृतित्व पर बार-बार और जमकर चर्चा की जाए. मगर इतना ही काफी नहीं है. ज्यादा जरूरी यह भी है कि राहुल जी की चुनी हुई किताबें पेपरबैक में उपलब्ध हों और उन्हें नए पाठकों के सामने लाने की कोशिश की जानी चाहिए.

ग्रंथावलियों के इस दौर में 'राहुल ग्रंथावली' की बात क्यों नहीं सोची जाती? राहुल जी की डायरियों, नोटबुकों और अन्य प्रकार की ढेर सारी सामग्री का उद्धार कब होगा? 'राहुल स्मृति' पर नजर डालने के बाद ऐसे सवाल उठते हैं.

इस पुस्तक के बारे में एक और बात गौर करने लायक है. राहुल जी वैचारिक स्तर पर आखिरी समय तक जिस खास राजनैतिक दल से जुड़े रहे, उसी की प्रकाशन-भुजा है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस. राहुल जी की मृत्यु के पूरे पचीस साल बाद इस संस्था को उनकी याद आखिर आ ही गई! यह क्या कम बड़ी बात है! वैसे, इस ग्रंथ के अस्तित्व में आने की एक अंतर्कथा भी है जिसके अनुसार प्रकाशक सोलहों आने श्रेय पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि इसके लिए सामग्री जुटाने का काम देहरादून के 'महापंडित राहुल सांकृत्यायन मेमोरियल ट्रस्ट' ने किया है.

—म.ना. भारती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रंगकर्म

गवाह का हलफिया बयान

नाटक करने और देखने वालों के लिए उपयोगी पुस्तक

हिंदी रंगकर्म: दशा और दिशा
डॉ. जयदेव तनेजा,
तक्षशिला प्रकाशन
अंसारी रोड, नई दिल्ली
कीमत: 150 रु.

हिंदी में नाट्य या रंग समीक्षा की इक्का-दुक्का पुस्तकें ही ऐसी हैं जिनमें सूझबूझ, प्रतिबद्धता और होम-वर्क का प्रमाण मिलता है. डॉ. जयदेव तनेजा की इस पुस्तक को ऐसी ही पुस्तकों में शुमार किया जा सकता है. उन्होंने लिखा है, "हिंदी में मौलिक नाट्य-लेखन की मौजूदा हालत बहुत खराब है." यह वक्तव्य तब भी सही था जब न तो नाटक छापने वाले प्रकाशक थे, न खेलने-देखने वाले रंगकर्मी या दर्शक. और अब भी सच है जब उपन्यास के बाद नाटक की किताबें ही ज्यादा छपती हैं. झेंप मिटाने के लिए अक्सर यह भी कह दिया जाता है कि हिंदी ही क्या, किसी भी भाषा में बहुत अच्छे नाटक इस समय नहीं लिख जा रहे हैं. ऐसा हो सकता है. मगर बुनियादी सवाल यह है कि क्या मराठी, बंगला या कन्नड़ और हिंदी की हालत में सचमुच कोई फर्क नहीं? और अगर है तो क्या ईमानदारी से इस फर्क के मूल कारणों की बे-झिझक गहरी पड़ताल नहीं करनी चाहिए?

लेखक के इन उद्‌गारों में एक ओर तो आजादी के बाद की रंगकर्म की दशा की पैनी पकड़ का परिचय मिलता है, दूसरी ओर उनकी गहरी संवेदना की झलक मिलती है. सच तो यह है कि हिंदी रंगकर्म की दशा कुछ बहुत अच्छी नहीं रही है और यह भी सच है कि कभी किसी ने कारणों को जानने की कोशिश भी नहीं की. होता यही रहा है कि हिंदी नाटककार रंगकर्म से दूर ही रहा है. कारण आर्थिक भी रहे हैं और कलात्मक भी. दूसरी यह बात थी कि अच्छे नाटक के अभाव में अच्छा रंगकर्म भला कैसे संभव है?

ऐसी बात नहीं है कि रंगकर्मी और नाटककार में कभी संबंध बने ही नहीं. मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और डॉ. लक्ष्मी नारायण लाल ने अच्छे निर्देशकों के साथ तालमेल बिठाया. ऐसे गठजोड़ों के परिणाम बहुत लाभदायक रहे. हिंदी रंगमंच कुछ अरसे के लिए उच्च कीर्तिमान स्थापित कर पाया. परंतु यह आदान-प्रदान ज्यादा दिन तक नहीं चला. कभी तो निर्देशक का अहं आड़े आया तो कभी लेखक के नखरे. लेखक के अनुसार बेशक नए हिंदी रंगमंच के उद्‌भव और विकास में निर्देशक की निर्णायक भूमिका रही है और दो एक अपवादों को छोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर के लगभग सभी निर्देशक अहिंदीभाषी ही रहे हैं. यही कारण है कि "हमारे अधिकांश वरिष्ठ राष्ट्रीय नाट्य निर्देशकों के हिंदी के प्रति अज्ञान, अल्पज्ञान या अवज्ञाभाव ने 'तंत्र और तकनीक' या 'फोकबाजी' को अतिरिक्त महत्व देकर नाटककार को रंगमंच के बाहर का आदमी सिद्ध कर दिया." वे चुटकी लेते हुए कहते हैं, "यों भी अपनी भाषा के नए नाटक से जूझने के बजाय दूसरी भाषाओं के परीक्षित सफल नाटकों को अपनी भाषा में ढंग से परोस भर देकर वाहवाही लूटने का काम ज्यादा आसान और लाभदायक है."

> **"अधिकांश वरिष्ठ नाट्य निर्देशकों के हिंदी के प्रति अज्ञान, अल्पज्ञान या अवज्ञाभाव ने 'तंत्र और तकनीक' या 'फोकबाजी' को अतिरिक्त महत्व देकर नाटककार को रंगमंच के बाहर का आदमी सिद्ध कर दिया"**
>
> इसी पुस्तक से

तनेजा एकआयामी टिप्पणी नहीं करते, वे 'समकालीन हिंदी नाटक' नामी लेख में नाटककारों की भी खबर लेते हैं. "मोहन राकेश, जगदीशचंद्र माथुर, शंकर शेष और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के निधन ने मौलिक नाट्य-लेखन को भारी धक्का पहुंचाया. लेकिन सवाल यह है कि धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मुद्रा-राक्षस, रमेश बक्षी, बृजमोहन शाह, विपिन अग्रवाल, मणि मधुकर, बलराज पंडित और दयाप्रकाश सिन्हा जैसे बहुसंख्य नाटककारों को क्या हो गया है?"

लेखक जब नाट्य समीक्षा पर आता है तो वह भी बहुआयामी होती है. वे भाषा, मंच विधान, रंगसज्जा, वेशभूषा के साथ-साथ अभिनय और निर्देशन पक्ष पर भी टिप्पणी करते हैं. 'छोटे सैय्यद, बड़े सैय्यद' की समीक्षा में वे लिखते हैं, "हिंदी नाट्य भाषा की दृष्टि से मोहन राकेश के बाद सुरेंद्र वर्मा ही अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. एक ओर सूक्ष्म, गहन भावों को व्यक्त करने में समर्थ बोलचाल की सरल किंतु विस्फोटक जीवंत भाषा का उपयोग किया है, तो दूसरी ओर संस्कृतनिष्ठ किंतु समकालीन लय-विधान से युक्त संवेदनशील नाट्य भाषा का."

गिरिराज किशोर के नाटक 'प्रजा ही रहने दो' के बारे में उनका कहना है, "शब्द बाहुल्य तथा भाषा की एकरूपता से उत्पन्न होने वाली एकरसता इस नाटक की एक बड़ी सीमा है."

डॉ. तनेजा की यह पुस्तक, जिसे उन्होंने 'पिछले लगभग एक दशक के हिंदी रंगकर्म के एक चश्मदीद गवाह का हलफिया बयान' कहा है, उनकी पहली पुस्तक "समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच" की अगली और परिमार्जित कड़ी है. उन्होंने इसमें एक ही नाटककार, एक ही निर्देशक, एक ही संस्था का एक ही स्थान पर क्रमबद्ध लेखा-जोखा देने का प्रयत्न किया है. जैसे समकालीन हिंदी नाटकों के विवेचन के पश्चात् उपन्यासों का मंचावतार, कहानी का रंगमंच, काव्य-नाटक और मंच आदि हिस्सों में बांटकर समीक्षाओं का संकलन किया है. इससे इस पुस्तक की उपादेयता न केवल रंगकर्म से जुड़े लोगों के लिए बढ़ गई है बल्कि यह नाट्य में रुचि लेने वाले सामान्य दर्शक को भी रंगकर्म की सूक्ष्म बातों का बहुत सरल ढंग से परिचय देती है. समीक्षकों को भी इस पुस्तक से दो चार गुर की बातें पता चल जाएंगी, खास तौर पर उस तरह के समीक्षकों को तो जो गोल्दोनी के नाटक को मोलियर का नाटक बताने जैसी गलतियां करते हैं.

—जे.एन. कौशल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

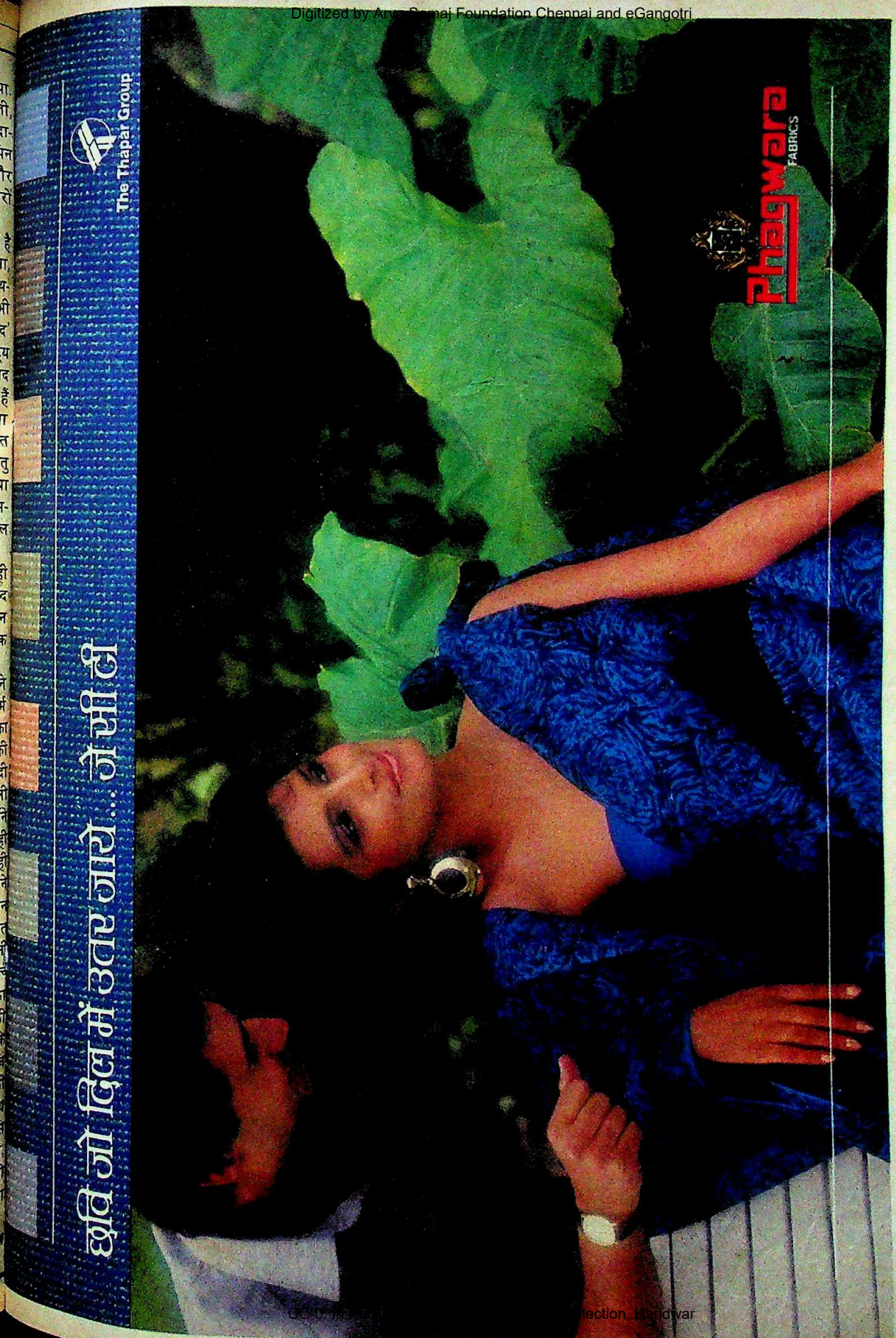

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Contract. JCT.20103/88-1 HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय संग्रहालय

रूसियों की सौगात

बेशकीमती चीजें देख आंखें चुंधिया जाएंगी

यह तहे दिल से दी गई सौगात है. सोवियत संघ के दिल क्रेमलिन से अवर्णनीय खूबसूरती वाला जो खजाना नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 21 सितंबर से 20 नवंबर तक होने वाली प्रदर्शनी के लिए आ रहा है वह इससे पहले शायद ही कभी सोने के गोल गुंबद से बाहर आया हो.

इसीलिए यह संग्रह भारतीय अधिकारियों के सुपुर्द करते समय रूसी विशेषज्ञों की धड़कनें बढ़ गई थीं. छोटे-छोटे बसरा मोतियों से लेकर हीरे-जवाहरात गिनने में तकरीबन एक महीने का समय लग गया. जवाहरातों से जड़ी सोने की एक मूर्ति पर तो एक वर्ग इंच में ही 136 जवाहरात लगे हैं.

इन 98 कलात्मक चीजों में सबसे दुर्लभ है, 17वीं शताब्दी में बना 'इवान द टेरेबल' के बेटे दीमित्री के ताबूत का चांदी से मढ़ा ढक्कन. यह नीलम, मणियों और चिड़िया के अंडे के आकार के पन्नों से जड़ा है.

प्रदर्शनी में 12वीं सदी की बेशकीमती चीजों से लेकर इस सदी का दंतकथाओं वाला सोने का अंडा तक होगा. इनमें राजचिन्ह से लेकर जवाहरात, जार और जरीना के वस्त्र तथा बर्तन, नीलमणियों से जड़ी बाइबल भी हैं.

कैथरीन द्वितीय का चांदी, कढ़ाई वाला गाउन जिसका पीछे लटकने वाला पल्लू ही 20 किलो का था और पीटर तृतीय के वस्त्र प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण होंगे. लेकिन शायद सबसे अनोखी चीज है सोने के अंडे. एक अंडे पर रेलगाड़ी बनी है और दूसरे पर जहाज. पर सबसे प्रभावशाली वह अंडा है जिसके गहरे हरे खोल पर चांदी से साइबेरिया का नक्शा बना है. 1900 में बना था जब पहली ट्रांस-साइबेरियन रेलगाड़ी शुरू हुई थी. अंडे में प्लेटिनम और सोने की छोटी-सी रेलगाड़ी है जिसमें इंजन और पांच डिब्बे हैं. सोने की एक चाभी भी है जिससे यह खिलौना रेलगाड़ी चलती है.

पर इन सबके लिए परदे के पीछे काफी जोड़तोड़ भी हुई. राष्ट्रीय संग्रहालय के उत्साही निदेशक डॉ. लक्ष्मी सिहारे कहते हैं, "हर निदेशक ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहता है. कुछ वस्तुओं के लिए तो साफ मना कर दी थी. पर कुल लेन-देन में बराबरी रखी गई, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के साथ ऐसा नहीं हो सका. उन्होंने अपने वादे नहीं निभाए."

क्रेमलिन के जवाहरातों को देखकर चोरों को भी ईर्ष्या होगी. इसलिए अभूतपूर्व सुरक्षा है. राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद 100 परिचायकों और पहरेदारों के अलावा 36 हथियारबंद रक्षक मुस्तैद रहेंगे. सीबीआई और दूसरी खुफिया एजेंसियों के लोग भी हरेक को भांपते हुए वहां होंगे. सिहारे कहते हैं, "राष्ट्रीय संग्रहालय पूरी तरह चाक-चौबंद है, आप किसी भी तरह की खतरे की बात का नाम लीजिए वह हमारे पास मौजूद है. उन्हें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी—रूस की यह विरासत फिर कभी इस तरह सामने नहीं होगी.

चित्र सौजन्य: राष्ट्रीय संग्रहालय

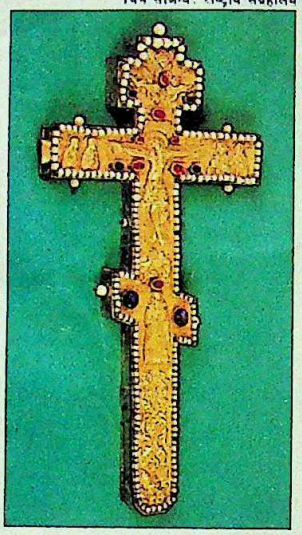

■ (बाएं से) दीमित्री के ताबूत का रत्नजड़ित ढक्कन और क्रॉस

■ (बाएं से) सोने का अंडा; धर्मगुरु की टोपी और इमान्युएल की मूर्ति: बेशकीमती धरोहर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करे सारा परिवार 'अपना घर' ऐसा उपहार

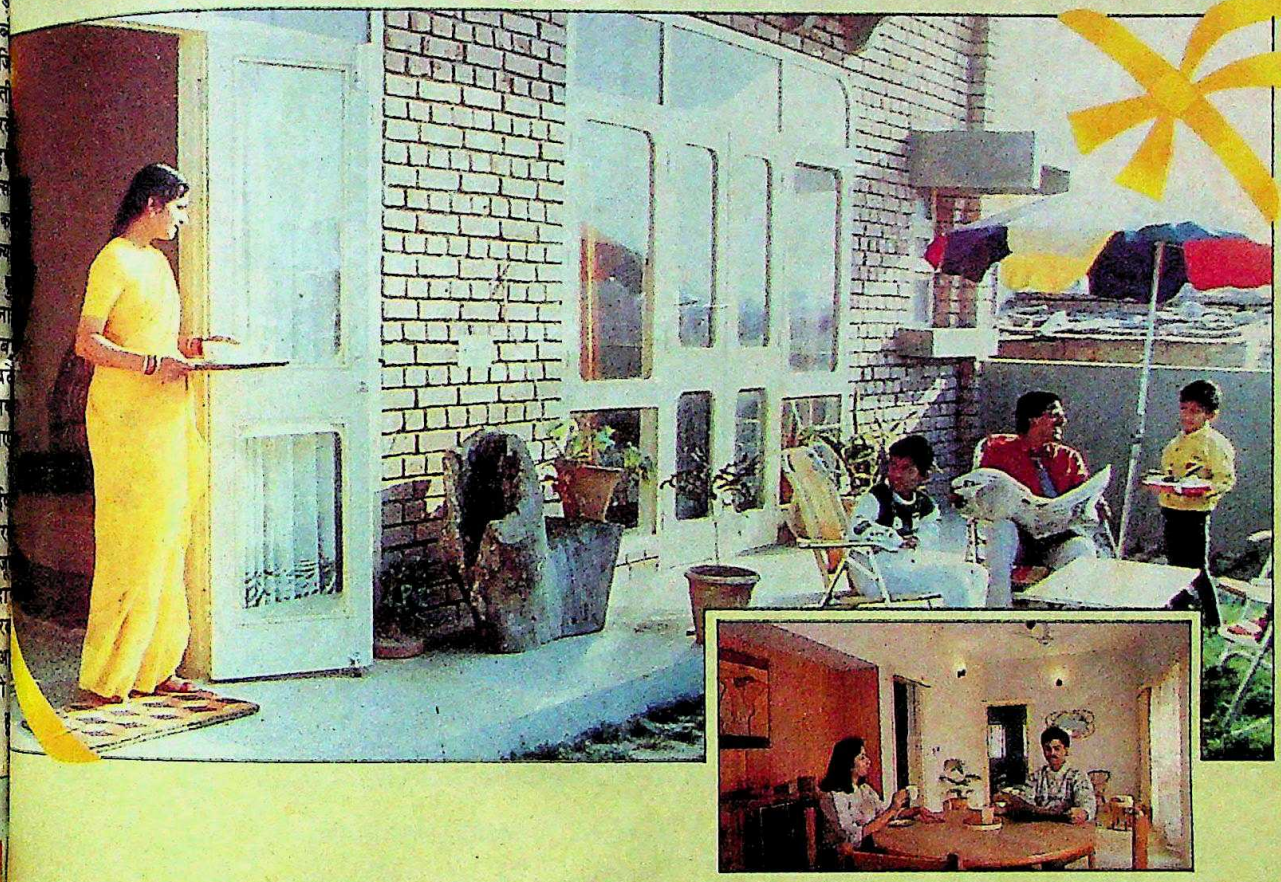

घर जिसके साथ है लॉन और किचन गार्डन
थ ही शापिंग सेन्टर की सुविधा भी.

ाना के घर सिर्फ चार दीवारें और छत ही नहीं बल्कि उनमें बसी है
एक सुरुचि-पूर्ण शैली. हर घर के साथ आपके लिए है बाहर की ओर
और पीठ की ओर किचन गार्डन. हर घर में आधुनिक निर्माण की
ाकनीक. यानि आशियाना में घर बुक करना आपके लिए पूर्ण

ी आशियाना में आपके लिए हर आधुनिक सुविधा की व्यवस्था है.
ारों की खरीदारी के लिए शापिंग सेन्टर 'खजाना,' मनोरंजन के
ल, अस्पताल, सिनेमा घर, बच्चों के लिए आधुनिक स्कूल. यही
एक प्राकृतिक परिवेश में हरे भरे पार्कों और उद्यानों की
के बीच. एक स्वच्छ सुन्दर वातावरण के बीच है न सभी
ुविधा अन्दाज़! उस जीवन का जो हमेशा से आपके
ी चाह है.

ी है समय, इस चाह को साकार रूप देने का.
शियाना 1990 में बन कर पूर्ण होने के अपने लक्ष्य
ओर बढ़ रहा है. आज ही 7 प्रकार के निर्मित
घरों और 6 आकारों के प्लॉटों में से अपनी पसन्द चुनिए और निश्चिंत
हो जाइये.

विशेषताएं :

- प्लॉट प्राप्त कीजिए 1988 में और निर्मित घर 1989 में विभिन्न चरणों में.
- तेज़ी से विकसित हो रहा है – 10 नमूने के घर तैयार, 300 घरों का निर्माण जारी. 25 कि.मी. सेक्टर मार्ग तैयार, बिजली-पानी की व्यवस्था का कार्य जारी.
- सुविधा जनक बुकिंग राशि. आसान ब्याज-मुक्त किस्तों में भुगतान.
- आवासीय ऋण उपलब्ध. 15 वर्षों में चुकाईये.

अन्सल आशियाना लखनऊ

विस्तृत विवरण के लिए लिखें या सम्पर्क करें :

अन्सल हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कं० लि०

2 चायना बाजार रोड, (तुलसी सिनेमा के पीछे)
लखनऊ-226 001 फ़ोन : 48554.

पंजीकृत कार्यालय :

15 अपर ग्राउण्ड फ्लोर, इन्द्र प्रकाश
21 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001.
फोन : 331-7015 टेलेक्स : 031-62626 ANSL IN.

ON-LINE/AHL/FP-88

SEAL OF ANSAL DEPENDABILITY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• इन दिनों बंबई में जिस चीज ने लोगों को अपने आकर्षण में बांधा हुआ है वह है 'डर्टी-डांसिंग'. इसी नाम वाली फिल्म के संगीत पर आधारित यह नृत्य कार्यक्रम अब दूसरे शहरों में भी लोकप्रिय होने लगा है. पिछले पखवाड़े जाने-माने नर्तक **हेमू** और **फरहा** की जोड़ी ने फिल्म की आठ धुनों पर नृत्य पेश किए और सभी कार्यक्रमों में 'हाउस-फुल' रहा. फरहा बताती हैं, "भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए हमने इन नृत्यों में से कुछ नाजुक किस्म के हिस्से निकाल दिए हैं." लेकिन विडंबना यह कि इसी बात ने बंबई शहर के दर्शकों को बेहद तकलीफ़ पहुंचाई है.

नाम भोजानी

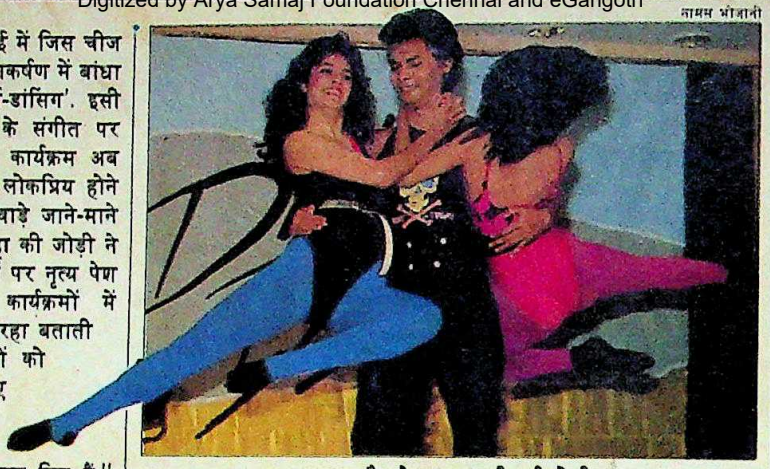

फरहा और हेमू: नाच की नई टोली

• दिल्ली पुलिस की यह युवती हजारों चालकों और बड़े-बड़े लोगों को अपने इशारों पर चलाने लगी है. राष्ट्रपति भवन के सामने

सर्वजीत: इशारों की बात

प्रशांत पंजियार

जहां किसी जमाने में कत्थक की लय पर ट्रैफिक को नियंत्रण करने वाला सिपाही खड़ा रहता था वहां इन दिनों 21 वर्षीया **सर्वजीत कौर** ड्यूटी पर तैनात रहती हैं. एक हवलदार की बेटी सर्वजीत के प्रशंसकों की संख्या अच्छी-खासी हो चुकी है. वे बताती हैं, "हर कोई रुककर मुझे देखता है. यहां तक कि प्रधानमंत्री भी मुझे बहुत गौर से देखते हैं." अपने शुरू के अनुभव के बारे में सर्वजीत का कहना है, "पहले तो मेरी बाहें बुरी तरह दर्द करती थीं. पर अब तो इसकी आदत पड़ चुकी है."

सचना फाउंडेशन

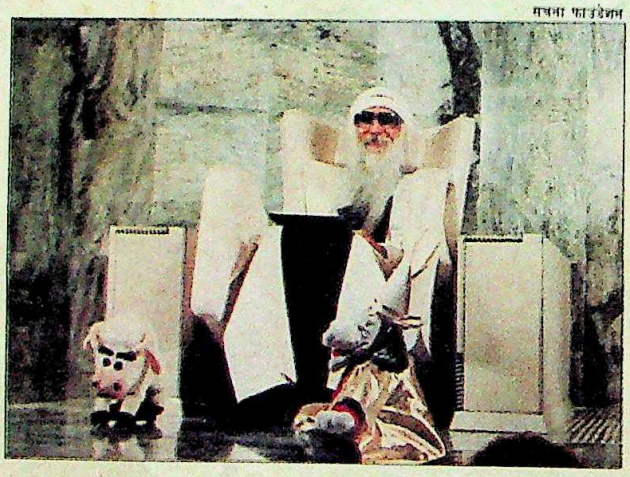

रजनीश: नया खिलौना

• 'भगवान' **रजनीश** ने नया खिलौना खोज निकाला है. यह एक स्वचालित सुअर है जिसका इस्तेमाल उन्होंने पुराने देवी-देवताओं संबंधी अपने नए म्यूजियम का उद्घाटन करने के लिए किया. इस म्यूजियम में कई तरह के जानवर व परिंदे जमा हो चुके हैं. म्यूजियम के बारे में उनका कहना है कि यह उन

"मूर्खों को समर्पित है जिन्होंने जानवरों को तो भगवान का दर्जा दे दिया पर खुद अपने भीतर नहीं झांकते." उन्होंने आगे कहा, "कानूनी झमेलों से फर्क नहीं पड़ता. दुनिया भर की अदालतों की मूर्खता मुझे दिलचस्प लगती है."

एस. एस. चुघकली

• **दिलीप वेंगसरकर** ने बंबई दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन स्थापना की है जिसका लक्ष्य हर मगर गरीब युवा खिलाड़ी को इंग्लैंड भेजना है. ऐसे दो खिलाड़ियों ने उनसे लंदन आने-जाने लिए किराए की मांग की थी तो तुरंत उनकी सहायता नहीं कर थे. इस घटना से उन्हें तुरंत विचार आया. उन्होंने अपने प्रिय बैट को नीलाम करने फैसला किया जिस पर उन्हें लाईस द्विशती मैच के दौरान बड़े खिलाड़ियों के हस्ताक्षर लिए लेकिन नीलामी से पहले ही बंबई एक पुराने मजदूर नेता ने एक लाख रुपए में सौदा पटा लिया. इस से यह फाउंडेशन बना.

वेंगसरकर: होनहारों के लिए

• इस बार हिंदुस्तानी खूबसूरत की ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है साल के लिए 'मिस-इंडिया' गई 23 वर्षीया **डॉली मिनहास** आठ महीने बाद होने वाली सुंदरी' प्रतियोगिता के लिए संजो रही हैं. उनके सपने यहीं सीमित हों ऐसी बात नहीं. प्रतियोगिताओं के अलावा दिनों आईएएस की भी तैयारी रही हैं और लिखित परीक्षा आधा रास्ता पार भी कर चुकी डॉली इंटरव्यू की दहलीज भी कर लेती हैं तो यकीनन भारत अफसरशाही के लिए अब तक सबसे खूबसूरत उपलब्धि होगी.

डॉली: खूबसूरत सपने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फरेब का पर्दाफाश

सरकार द्वारा कामयाबी के बड़े-बड़े दावों और भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद एक दशक से जन्म दर घटी नहीं. भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम मुख्यत: एक फरेब ही है. सरकारी बयान और आंकड़े भ्रामक हैं. असलियत का ब्यौरेवार विश्लेषण.

आवरण कथा.....22

कमर कसने की कसरत

केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी आगामी चुनावों की तैयारी में जुट गई है. नई चुनावी रणनीति में कार्यकर्ताओं की भागीदारी को प्रमुखता दी गई दिखती है. उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के अलावा काम की निगरानी के लिए कार्यदल गठित किए जा रहे हैं.

खास रपट.....14

सरकार का कसता शिकंजा

पिछले पखवाड़े दूरदर्शन के महानिदेशक भास्कर घोष का तबादला साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित था. आगामी आम चुनावों के मद्देनजर सत्तारूढ़ पार्टी दूरदर्शन सरीखे शक्तिशाली माध्यम का अपने प्रचार के लिए जमकर इस्तेमाल करना चाहती है.

खास रपट.....50

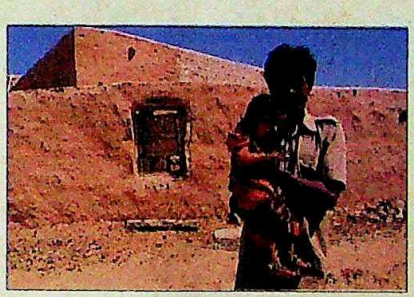

कन्याओं के कत्ल की कुप्रथा

राजस्थान के सामंती विचारों वाले भाटी राजपूतों में नवजात कन्याओं की हत्या की प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. नतीजतन, पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या बहुत कम हो गई है. अब इस कुप्रथा के खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं.

खास रपट.....32

लापरवाही की लपेट में

पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन एअरलाइंस के यात्रियों को लेट होती उड़ानों और आरक्षण रद्द होने जैसी मुश्किलों से दो-चार होना पड़ा है. विमानों की कमी हालांकि इसकी एक बड़ी वजह है पर मामला दरअसल इससे भी ज्यादा गंभीर है. एक विश्लेषण.

विशेष लेख.....78

पश्चिमी बुखार का चढ़ता पारा

देश भर के किशोरों में फैशन क्रांति की हवा चल पड़ी है. उनकी पसंद भले ही पश्चिमी दुनिया से प्रभावित हो, पर फैशन की अगुआ नई पीढ़ी में खूबसूरत दिखने की इच्छा बलवती होती जा रही है. और यह खूबसूरती भी मुख्यत: पहनावे का ही है. एक लेखाजोखा.

विशेष लेख.....82

अगले पन्नों पर

कसौटी.....8
तेवर.....9
राजरंग.....10
हिंदोस्तां हमारा.....12
बीता पखवाड़ा.....13
खास रपट
इंका: कमर कसने की कसरत.....14
वाममोर्चा:
घटकों ने बजाई खतरे की घंटी.....18
आवरण कथा
परिवार नियोजन कार्यक्रम:
फरेब का पर्दाफाश.....22
खास रपट
राजस्थान: कन्या के कत्ल की कुप्रथा.....32
आजकल
विपक्षी एकता: औपचारिकता पूरी हुई.....35
उत्तर प्रदेश: घर का सम्मोहन.....37
मध्य प्रदेश: सभी तीर नाकाम.....38
बिहार: सख्ती का स्वांग.....40
पंजाब: अप्रत्याशित विपत्ति.....46
बात पते की.....48
खास रपट
दूरदर्शन: सरकार का कसता शिकंजा.....50
राज्य-दर्पण.....53
विशेष लेख
नर्मदा घाटी परियोजना:
विरोध की घनी घाटियों में.....54
तस्करी: कंचन की मादक माया.....58
व्यापार चक्र.....65
कारोबार
आठवीं योजना: चादर भर
पांव पसारने की बात.....66
जीटीसी: कई सवालों की जद में.....71
पास पड़ोस
बर्मा: बगावत का बढ़ता दायरा.....76
विशेष लेख
इंडियन एअरलाइंस: लापरवाही और
लेट-लतीफी की लपेट में.....78
किशोरों का फैशन प्रेम:
पश्चिमी बुखार का चढ़ता पारा.....82
खेलकूद
ओलंपिक:
शानदार आयोजन से बढ़ी शान.....86
रंगमंच
रानावि: एक और पटाक्षेप.....89
कला
चित्रकला: नए कलाकारों का जमाना.....90
सिनेमा
रुक्मिणी: औरत तेरे रूप अनेक.....94
शिक्षा
इंजीनियरिंग कॉलेज:
अध्यापकों का भारी अकाल.....95
विकास
जोड़ नहर: अटकती भटकती धारा.....97
किताबें.....99
टीवी
महाभारत: छोटे परदे पर बड़ी लड़ाई.....102
चर्चित चेहरे.....104

आवरण परिकल्पना: मंजुला पद्मनाभन
आवरण चित्र: टी.एस. सत्यन/यूनिसेफ

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहली नज़र में फ़िदा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बस, नज़र पड़ते ही आप जी-जान से न्यौछावर... यही तो है ऑप्टॉनिका का करिश्मा... जीवन भर के लिए... ऑप्टॉनिका, एकमात्र टीवी, जो आपकी नज़रों के सामने **ट्रू-लाइफ़ विज़न** का ख़ज़ाना खोलने को तैयार है.

ट्रू-लाइफ़ विज़न – सच्चाई का दर्पण... तराशी तस्वीरें... स्पष्ट और तीखी... **हाइ सेन्सिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर** की बदौलत, **कलर डिकोडर सर्किट** के कारण नैचुरल रंगों का स्वाभाविक दर्शन, **ऑटो लिनियरिटी कंट्रोल** की वज़ह से सही आकार... सही स्वरूप. **ऑप्टिमैटिक पिक्चर कंट्रोल** याने अपने आप ही कॉन्ट्रास्ट का मेल मिल जाना.

ऑप्टॉनिका – सुंदर, भरोसेमंद – जीवन भर के साथ का वायदा लिए...

ऑप्टॉनिका – पहली नज़र में ही आप इसके हो जाएंगे!

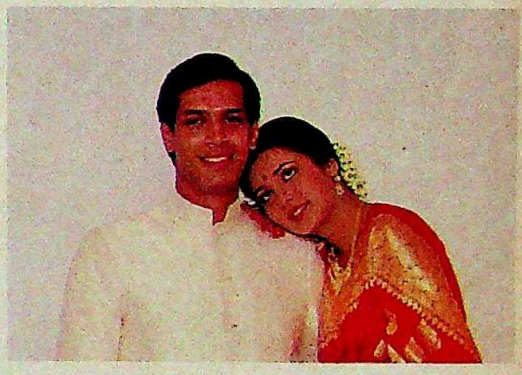

OPTONICA

ट्रू-लाइफ़ विज़न... ज़िंदगी भर के लिए!

CC-0. In Public Dom... dwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शाम की रंगीनियों में शानदार नज़र आएं.
ये ख़ूबसूरत शर्ट हर नज़र में समाएं.

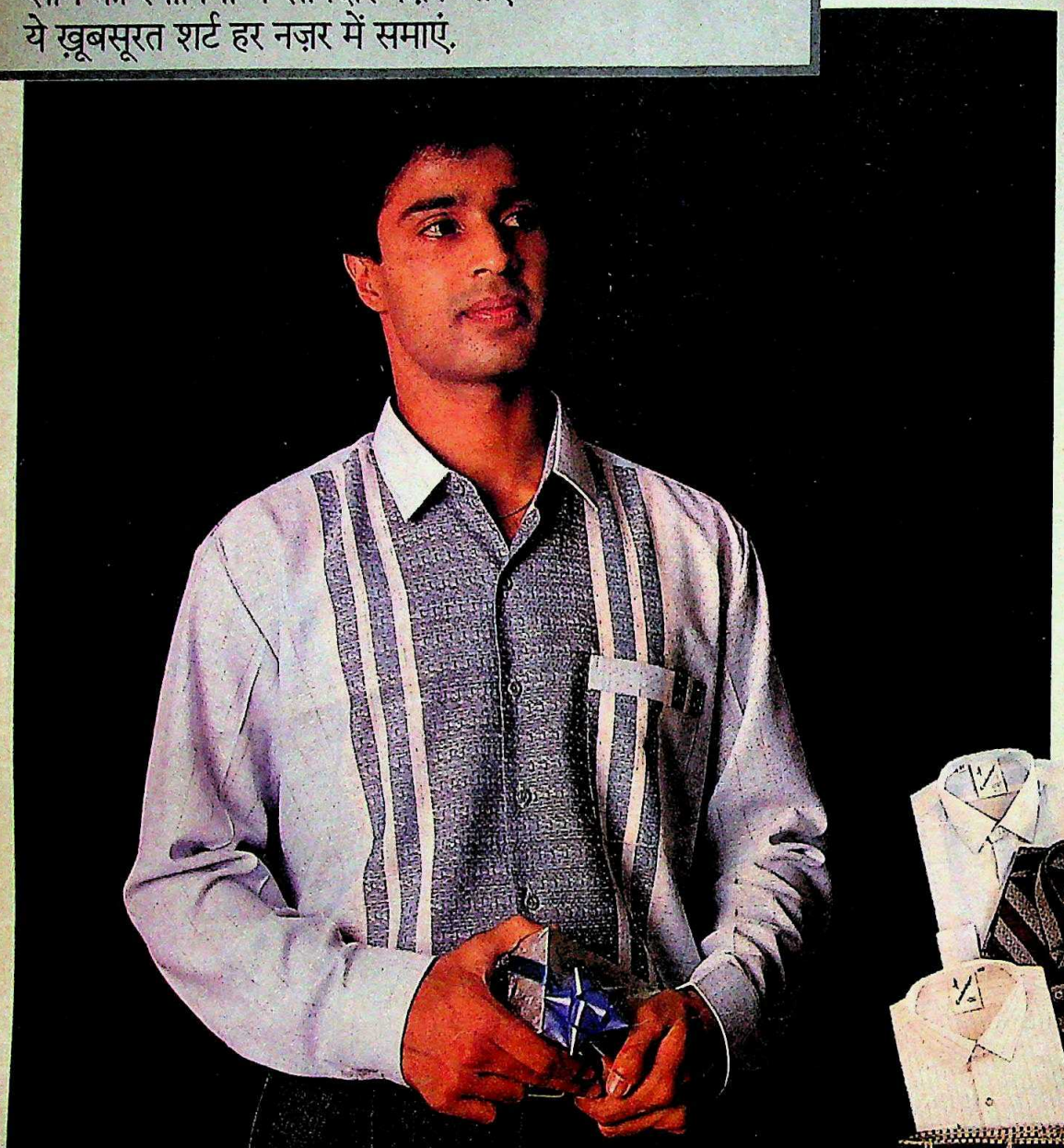

VENART 1

Cambridge®

हर मूड के लिए बनी हैं ये.
हर जेब के लिए सही हैं ये.

ईवनिंग शर्ट्स • ट्राउज़र्स • ऑफिस शर्ट्स • कैज़ुअल शर्ट्स • जीन्स

शर्ट: रु. ७० से रु. १८०
ट्राउज़र्स: रु. १५० से रु. २९०
जीन्स: रु. १५० से रु. २५०

कैम्ब्रिज

व्यापार संबंधी पूछताछ (स्थानीय):
सुशील एंड कंपनी, १४ ए, भवानी कॉम्प्लेक्स, भवानी शंकर रोड,
दादर (पश्चिम), बंबई ४०००२८.
व्यापार संबंधी पूछताछ (निर्यात):
कैम एन्टरप्राइज़ेस, १५ भवानी कॉम्प्लेक्स, भवानी शंकर रोड, दादर (पश्चिम), बम्बई ४०००२८.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 2, अंक: 24, 16-31 अक्तूबर, 1988

प्रधान संपादक
अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक
प्रभु चावला

संपादकीय विभाग
जगदीश उपासने, अशोक कुमार, विजय क्रांति, ओम प्रकाश सराफ, अरविंद मोहन मिश्र

प्रोडक्शन
अनिल शर्मा, सुबाचन यादव
सुनील सैनी

■ **संपादकीय कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली.

■ **मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:** इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

■ **मुख्य विज्ञापन कार्यालय:** 28 ए और बी, जोली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया, बंबई.

■ **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** के-9, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली • फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास • 74/1 सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर • 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता. • कॉपीराइट 1984, लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनियंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता. • लिविंग मीडिया इंडिया लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

नेपाल में 6 रुपए

शर्म से झुका माथा

सिओल में हुए 24वें ओलंपिक पर आवरण कथा 'पश्चिम को पछाड़ा पूरब ने' (15 अक्तूबर) बहुत रोचक लगी. लेकिन 'भारत: हर मैदान में मात' पढ़कर सिर शर्म से झुक गया. अपनी कमजोरियों और खराब प्रदर्शन को ढकने के लिए बहाने तराशने, एक-दूसरे की टांग खींचने, तिकड़मबाजी और अपने स्वार्थों को सर्वोपरि समझने का सिलसिला यदि इसी तरह चलता रहा तो ओलंपिक ही नहीं, एशिया स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भारत की यही दशा होगी.

—चरनजीत कुमार, फरीदाबाद (हरियाणा)

■ आवरण कथा में ही 'दवा के दम पर दगा' पढ़कर बहुत दुख हुआ. बेन जॉन्सन की इस हरकत ने उनके देश का नाम तो डुबोया ही, ओलंपिक खेलों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है. शायद आजकल के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा पर विश्वास नहीं रहा है, या उनमें खेल भावना लुप्त हो चली है. —हर्ष कुमार, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

■ निस्संदेह सिओल में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय गौरव को अपमानित करने जैसा है. इस प्रदर्शन से हर भारतीय आहत हुआ है.

—ओम बिश्नोई, श्रीगंगानगर (राज.)

सूर्य बन सकता है बशर्ते

खास रपट 'सात घोड़ों के रथ का कारवां' (15 अक्तूबर) पढ़ी. लगता है भारत की राजनीति में एक भयंकर भूकंप आने वाला है. सात घोड़ों का यह रथ चमकते सूर्य के समान भी हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि पता नहीं कौन-सा घोड़ा पागल हो जाए और रथ को दिशाहीन कर दे. —संजय शरण वर्मा, बुलंदशहर (उ.प्र.)

■ हर बार एक होने से पहले ही अलग हो जाने वाले विपक्षी दलों के नेताओं से मद्रास में हुए इस सम्मेलन के बाद कुछ उम्मीदें बंधती नजर आ रही हैं. विश्वनाथ प्रताप सिंह दक्षिण में लोकप्रिय हो रहे हैं, यह भी एक अच्छी बात है. बस डर यही है कि पता नहीं कब कौन-सा घोड़ा बिदक जाए और अब तक के किए-कराए पर पानी फेर कर रख दे.

—यशोधरा, नई दिल्ली

जनमत की जीत

मानहानि विधेयक का 'चुनौती के आगे चित' (15 अक्तूबर) होना लोकतंत्र की जीत है. प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाते हुए बिना शर्त वापस ले लिया, अच्छा किया. अब एक बात साफ हो गई है कि लोकतंत्र में देर से ही सही, जनमत को स्वीकारना जरूर पड़ता है. —ए. जैन, बड़ौत (उ.प्र.)

हर भारतीय आहत

आवरण कथा 'मंजिल अभी कोसों दूर' (30 सितंबर) में राजनीति, स्वार्थ, भ्रष्टाचार और आर्थिक अभाव की चौतरफा मार से दीन-हीन हो चुके भारतीय खेल जगत की सही समीक्षा की गई है. लेकिन इसके साथ इस सचाई को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि जिन देशों में क्रिकेट को ही प्राथमिकता दी जाती है, वे सभी भारत की ही तरह बाकी खेलों में पिछड़े हुए हैं.

—नरेंद्र सक्सेना, नौगांव (म.प्र.)

■ मार्गरेट अल्वा की बातों से तो यही लगता है कि वे असफलता के लिए पहले से ही तैयार बैठी थीं. हमारे प्रशिक्षक आधुनिकतम उपकरणों और खेल के मैदान की कमी का रोना रोते हैं तो खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को सैर-सपाटे का माध्यम ही समझते हैं. यानी ऊपर से नीचे तक पोल ही पोल है. यदि यही हाल रहा तो एक दिन हम एशिया स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग नहीं ले पाएंगे.

—राजेश मोहन चौधरी, इलाहाबाद (उ.प्र.)

नैतिक पराजय

'चौथे खंभे पर चोट' (30 सितंबर) एक तरह से कानूनी आतंकवाद ही है. हालांकि सरकार लोकतंत्र के कई तत्वों की पहले ही हत्या कर चुकी है पर इस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विधेयक से तो लोकतंत्र का जनाजा ही उठ जाता. सरकार ने इसे वापस ले लिया, वरना सरकार और उसके भ्रष्ट मंत्रियों को अभयदान देने वाला यह विधेयक राजीव के लिए राजनैतिक 'हाराकीरी' साबित होता.

—राम नगीना मौर्य, वाराणसी (उ.प्र.)

■ दरअसल यह चोट चौथे खंभे पर न होकर जनता के विश्वास पर थी जिसने सहानुभूति के आवेश में सरकार को भारी बहुमत से जिताया था. हड़बड़ाहट में इस विधेयक को पारित कर सरकार ने परोक्ष रूप से अपने ऊपर लगे घोटालों के आरोपों को कबूल ही किया है.

—आलोक कुमार शर्मा, खैरागढ़ (म.प्र.)

■ मानहानि विधेयक बिना शर्त वापस लिया जाना राजीव सरकार की नैतिक पराजय है. अब यह सरकार पत्रकारिता की आजादी और जनता के अधिकार के विरोध में कोई कदम उठाने का दुस्साहस नहीं करेगी. —बच्चू मुते, नागपुर (महाराष्ट्र)

■ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किया गया कोई भी प्रहार भारतीय जनता को बर्दाश्त नहीं होगा, यह इस विधेयक के व्यापक विरोध से साबित हो गया है. समूचे समाचार जगत ने अनूठी एकता की जो मिसाल कायम की वह निश्चय ही सराहनीय है.

—सुरेश छाबड़ा, रावतभाटा (राज.)

महंगा अनाड़ीपन

'रिश्तों व राजनीति की गुत्थी' (30 सितंबर) संजय सिंह की लोकप्रियता मिटाने का एक राजनैतिक षड्यंत्र ही साबित हुआ है. लेकिन सीबीआई ने जिस अनाड़ीपन से मामला निबटाया है उससे संजय को फायदा ही पहुंचा है. पहले हड़बड़ी में पास किए गए मानहानि विधेयक की वापसी और फिर संजय को मोदी हत्याकांड में दोषी साबित करने की असफलता— ये सिद्ध करती हैं कि राजीव के सलाहकारों की सभी राजनैतिक चालें उन्हें महंगी पड़ रही हैं. —दिलीप कुमार साह, पूर्णिया (बिहार)

■ आपने जिस निष्पक्षता से सैयद मोदी हत्याकांड का विश्लेषण किया है वह सराहनीय है. संजय पर लगाए गए आरोप एक राजनैतिक षड्यंत्र का ही हिस्सा लगते हैं, क्योंकि सीबीआई उनके खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं जुटा पाई. अब यह तो वक्त ही बताएगा कि यह षड्यंत्र दूषित राजनीति का परिणाम है या व्यक्तिगत रिश्तों की राजनीति का. —वैशाली गुप्ता, खुर्जा (उ.प्र.)

परिश्रम और निष्ठा

■ 'खयाल गायकी के धुरंधर' (30 सितंबर) मलिकार्जुन मंसूर ने साबित कर दिया है कि यदि व्यक्ति में लगन और निष्ठा है तो वह ऊंचाई की किसी भी हद को छू सकता है. गरीबी या किसी और तरह का सामाजिक प्रतिबंध उसमें बाधा नहीं बन सकते. —वीरेंद्र राय, आरा (बिहार)

अब भी अनदेखी

'धमकी भरा टेप' (30 सितंबर) में रुस्तम तीरंदाज ने टेप के रूप में सबूत पेश कर दिया है कि भिवंडी और अहमदाबाद में हुए दंगों में शिवसेना का ही हाथ था तो क्या अब भी शिवसेना पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा?

—सगीरुद्दीन नूरी, बरेली (उ.प्र.)

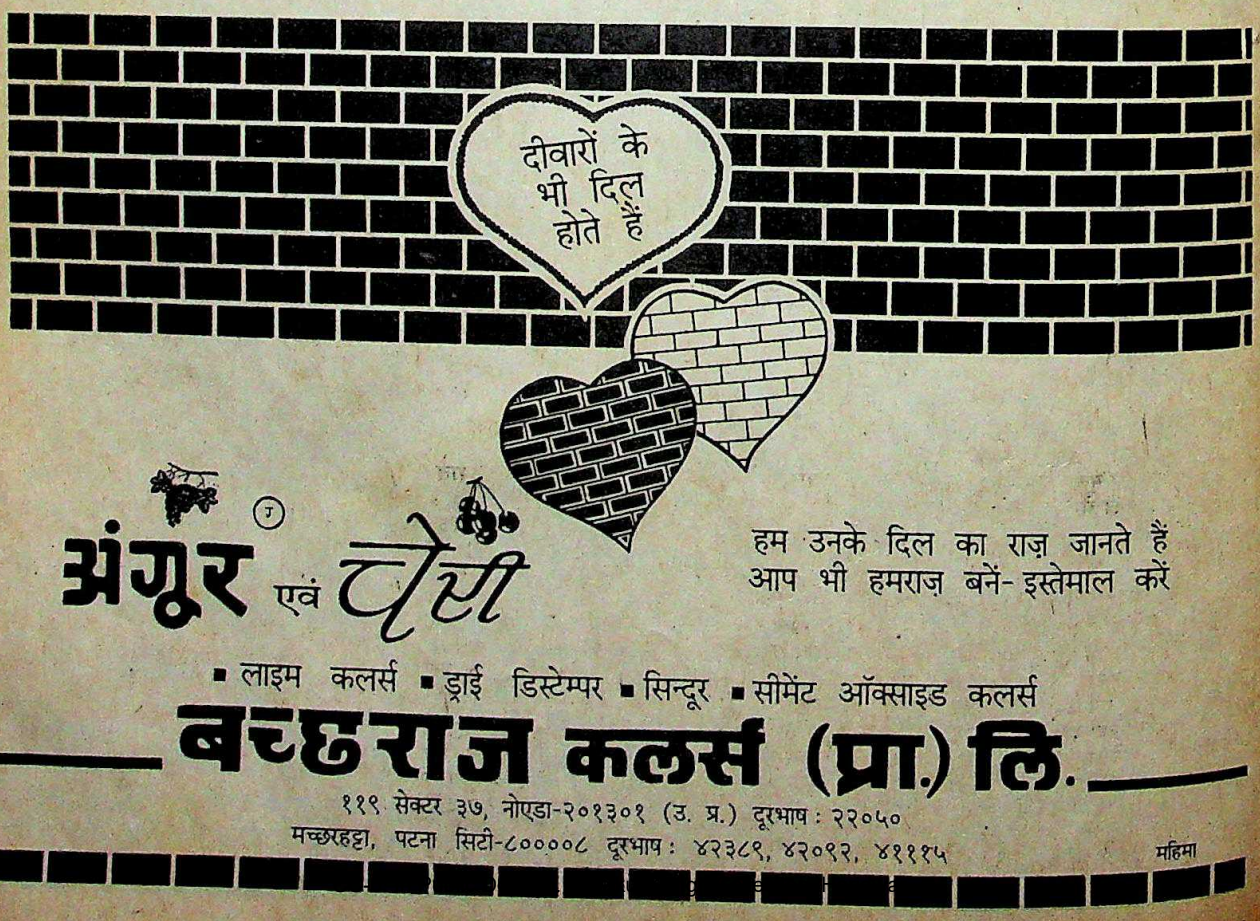

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्व-प्रसिद्ध शृंखला

पुस्तक महल की 30 पुस्तकों का
एक अनूठा प्रोजेक्ट

मूल्य: 15/- प्रत्येक
डाकखर्च: 4/- प्रत्येक
एक साथ चार पुस्तकें मंगाने पर डाकखर्च माफ

- प्रामाणिक पाठ्य-सामग्री
- प्रत्येक पुस्तक सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित
- सरस कथा शैली
- फोटोटाइप सैट
- बढ़िया कागज पर ऑफसैट छपाई
- वाजिब दाम

इस शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय जगत से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करना है।

उदाहरणार्थ 'रोमांचक कारनामे' में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो 'खोजें' में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। 'अनसुलझे रहस्य' में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर भूत-प्रेतों तथा रक्त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो 'खेल और खिलाड़ी' व 'वैज्ञानिक' क्रमशः जीवनी प्रधान पुस्तकें हैं। 'विनाश-लीलाएं' में प्रकृति के प्रलयंकारी रूप का चित्रण है तो 'दुर्घटनाएं' में मानवीय भूलों से हुई मर्मांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है। 'गुप्तचर संस्थाएं' तथा 'जासूस' में मकड़ी के जालों सी फैली जासूसी संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं तो 'प्रेरक-प्रसंग' किसी भी जहाज की तरह भटके हुए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ है।

कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को पूर्ण रूप से उजागर करने वाला एक सचित्र **'मिनि एनसाइक्लोपीडिया'** है।

इस शृंखला में प्रकाशित पुस्तकें:

विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल और खिलाड़ी 8. रिकॉर्ड्स-I 9. रिकॉर्ड्स-II 10. वैज्ञानिक 11. विनाश-लीलाएं 12. दुर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं 14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग 16. चिकित्सा-पद्धतियां 17. जासूसी-कांड 18. बैंक डकैतियां एवं जालसाजियां 19. क्रूर हत्यारे 20. सभ्यताएं 21. अनमोल खजाने।

तैयारी में/प्रेस में

- रोमांस-कथाएं
- भूत-प्रेत
- दुस्साहसिक खोज यात्राएं
- राजनैतिक हत्याएं
- क्रांतियां

आमंत्रण:—

प्रोजेक्ट के लिए विद्वान लेखकों व अनुवादकों का सहयोग अपेक्षित है।

अपने निकट के बुकस्टॉल एवं रेलवे तथा बस अड्डों पर स्थित बुकस्टॉलों पर मांग करें अन्यथा वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता:—

पुस्तक महल, खारी बावली, दिल्ली-110006.
शोरूम: 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
बांच ऑफिस: 22-2, हिमायत रोड (शामा राव कम्पाउंड), बंगलौर-560027

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

वरदान बना अभिशाप

कहर बरपा देने वाले सूखे के बाद तबाही मचा देने वाली बाढ़! और यह क्रम बार-बार. साफ है कि प्रकृति यह एहसास करा देना चाहती है कि लोग जब पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसके नियमों की उपेक्षा करेंगे तो इसका नतीजा क्या कुछ हो सकता है. प्रकृति ने बिलकुल साफ कर दिया है कि मनुष्य की जिन कार्रवाइयों के चलते भयानक सूखा पड़ता है, उन्हीं के चलते बाढ़ भी आती है. इन कार्रवाइयों का क्रम और परिणाम इस प्रकार है—जंगल कटाई और इसके कारण पानी का जमाव और इसके कारण गाद भरना.

सूखे का मतलब सिर्फ बारिश की कमी नहीं है. इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इससे मिट्टी की नमी उड़ जाती है और भूमिगत जल का भंडार सूखने लगता है. और बाढ़ का मतलब सिर्फ बेहिसाब बारिश नहीं है. इसका मतलब बारिश के पानी का अनियंत्रित बहाव और उसके साथ नदियों की सतह पर मिट्टी भरना भी है. यह सब प्रकृति नहीं करती, मनुष्य करवाता है. प्रकृति की जो व्यवस्था है, जिसे मनुष्य ने चौपट कर दिया है, उसके तहत होता तो यह है कि वन और वनस्पति बारिश के पानी को सोख लेते हैं और जमीन के भीतर प्रवाहित कर देते हैं. एक विशेष प्रक्रिया के तहत यह पानी वहां से जलग्रहण क्षेत्रों और पन-ढालों से पूरे वर्ष धीरे-धीरे नदियों तक पहुंचता रहता है.

रेखाचित्र: अजीत नैनन

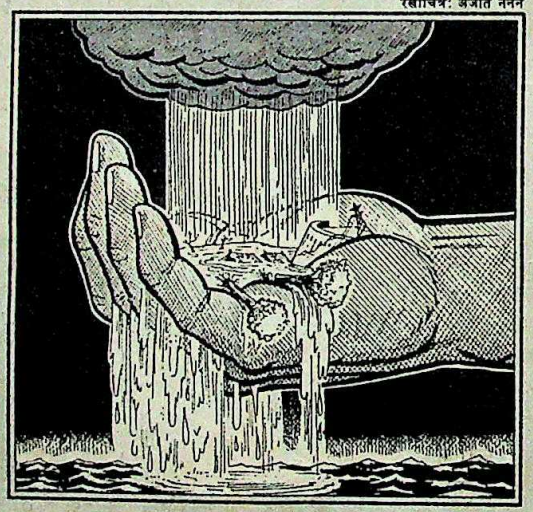

लेकिन जंगल की व्यापक कटाई से यह व्यवस्था चरमरा गई है. अब बारिश का पानी सीधे जलग्रहण क्षेत्रों में पहुंचता है और जमीन के भीतर सोखे जाने के बजाय जमीन की ऊपरी सतह को कुरेदता हुआ नदियों में पहुंच जाता है. इसके साथ बही मिट्टी नदी की सतह को ऊंचा कर देती है. नतीजा बाढ़ के रूप में सामने आता है. जो पानी वरदान होना चाहिए वह अभिशाप बन जाता है. और अधिकांश पानी समुद्र में पहुंच कर बरबाद हो जाता है.

नतीजा यह कि यह पानी जमीन के भीतर नहीं पैठता और भूमिगत जल का छीजता भंडार और छीजता जाता है. और तब अगर बारिश नहीं होती है तो सूखा धमक पड़ता है. लेकिन उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि एकाध साल बारिश न भी हो तो खेती और अर्थव्यवस्था पर उतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए जितना इन दिनों पड़ जाता है. राजस्थान के उदाहरण से साफ है कि वहां चार-पांच वर्षों में एक साल भी बारिश हो जाए तो वह सूखे वाले वर्षों में वनस्पति को बचाए रखने के लिए पर्याप्त है.

असली मुद्दा यही है. पानी की बरबादी को रोका जा सकता है. अगर इसे आसान, कम खर्चीले और मौलिक तरीकों से जमीन के अंदर सुरक्षित किया जा सके तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न भी हो मगर मनुष्य और मवेशी के लिए पीने का पानी तो पर्याप्त मिल सकता है. पिछले चालीस वर्षों में सरकार की एक सबसे बड़ी नाकामी यह भी रही है कि उसने जमीन और जल के प्रबंधन की समन्वित और व्यापक योजना तैयार नहीं की है. गरीबी हटाने के उपायों में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी.

15 वर्ष पहले जब भूक्षरण और पानी की बरबादी को आर्थिक विकास में बाधक बताया जाने लगा था तो इंदिरा गांधी ने केंद्रीय भूमि उपयोग आयोग की स्थापना के निर्देश दिए थे. लेकिन इस पर आगे कुछ हुआ नहीं. छठी योजना में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि "भूससाधन का निरंतर ह्रास आर्थिक प्रगति की रफ्तार को सबसे बड़ा खतरा है." लेकिन भूमि प्रबंधन के लिए इस लफ्फाजी के अलावा कुछ नहीं किया गया है. राजीव गांधी ने भी अपने पहले महत्वपूर्ण वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया था कि बेहतर भूमि प्रबंधन के अभाव में कई तरह की सामाजिक-आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं. इस समस्या से जूझने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड और राष्ट्रीय भूमि उपयोग व संरक्षण बोर्ड की स्थापना की. पहले वाले बोर्ड को पर्याप्त अनुदान नहीं मिला और उसने कुछ नहीं किया. और दूसरे वाले बोर्ड की तो दो साल से कोई बैठक ही नहीं हुई.

राजीव गांधी के कार्यकाल में सूखे का दौर भी लंबा रहा है. उन्होंने पर्यावरण के प्रति जो अपनी चिंताएं जाहिर कीं उन्हें देखते हुए लगता था कि सूखे को टालने की कुछ मौलिक कार्रवाई की जाएगी. भूमिगत जल के संरक्षण के लिए जमीन के समतलीकरण, जगह-जगह खड्डों की खुदाई, छोटे-छोटे तालाबों और नालियों के निर्माण और सस्ती किस्म की घास लगाने की जरूरत है. देश भर के गांवों में करीब पांच लाख छोटे-छोटे तालाब तो हैं लेकिन उनकी नियमित सफाई और उन्हें गहरा करने की जरूरत है.

चालू पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में सरकार ने बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के तहत करीब 15 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए प्रति हेक्टेयर 44 हजार रु. खर्च किए. लेकिन वनीकरण और भूमि व जल संरक्षण के लिए उसने प्रति हेक्टेयर 107 रुपए यानी 1800 करोड़ रु. से ज्यादा खर्च नहीं किए. गलत प्राथमिकताओं के प्रति अब वैज्ञानिक भी सचेत होने लगे हैं. देश की पांच करोड़ हेक्टेयर सिंचित जमीन में से 2.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन भूमिगत जल पर निर्भर है.

फिर भी, 1987 के दौरान जब सूखे का संकट भयावह हो गया था और सूखा राहत योजनाओं की भरमार थी, तब भी सूखे को टालने की व्यवस्था करने का कोई संगठित प्रयास होता नहीं दिखा था. बहरहाल, इस साल इंद्र देवता की मेहरबानी से जो पानी वरदानस्वरूप मिला है, वह थोड़े समय के लिए तो राहत जरूर दिलाएगा. लेकिन अफसोस की बात यही है कि कि इसमें से अधिकांश पानी बरबाद हो जाएगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

—आर.के. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया

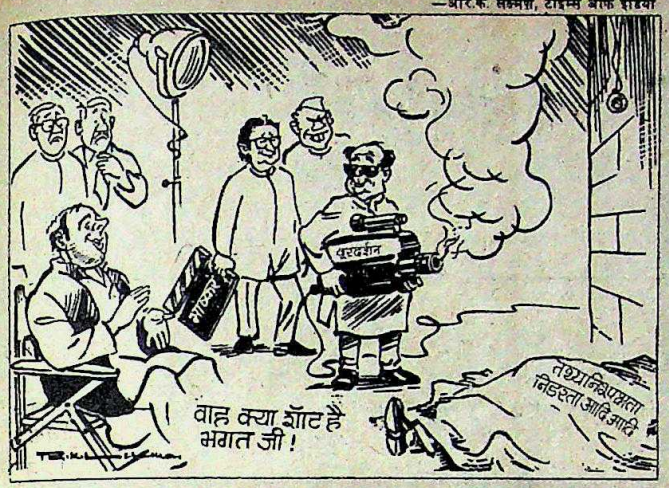

• जैसे जनता पार्टी सरकार के दौरान किसी ने जयप्रकाश नारायण की बात नहीं सुनी वैसे ही आज जब मैं अपनी बात कहता हूं तो कोई नहीं सुनता.

■ **कमलापति त्रिपाठी,** *स्वतंत्र भारत*

• मंत्री या मुख्यमंत्री होना— केंद्र में हो या राज्य में— यह किसी को न विरासत में मिलता है, न किसी की ठेकेदारी है.

■ **नारायणदत्त तिवारी,** *रविवार*

• मार्क्सवादी पार्टी तो कांग्रेस (इ) को वर्ग शत्रु मानती है.

■ **ईएमएस नंबूदिरिपाद,** *आज*

• हर जगह पार्टियों के बॉस ही अंतिम फैसला करते हैं. ये बॉस देश की राजनैतिक आजादी के लिए खतरा बन गए हैं. —**सोमप्पा रायप्पा बोम्मई** (मुख्यमंत्री, कर्नाटक), *जनसत्ता*

• सरकार की बात छोड़िए. आप प्रेस वाले प्रेस काउंसिल को कितनी अहमियत देते हैं?

■ **अमरेंद्र नाथ सेन** (अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल), *दिनमान*

• इस्तीफा देकर (लोकसभा से) मैं दिल्ली में कैसे रहूंगा. क्या चार हजार रुपए महीने इस कोठी का किराया दे सकता हूं? यह राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू और आरिफ (ही) कर सकते हैं.

■ **रामधन,** *नवभारत टाइम्स*

• मैं दार्शनिक हूं, राजनीतिक नहीं.

■ **सुवास धींसिंग,** *इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया*

• नेहरू का समाजवाद मैं नहीं जानता. मैं तो पूरी तरह व्यावहारिक आदमी हूं और हमारा समाजवाद व्यावहारिक किस्म का है.

■ **विजय कुमार रांजाल,** *वीक*

• मैं तो शौक के लिए अभिनय करती हूं.

■ **अमला,** *धर्मयुग*

• एक बेहद अच्छे पति की ख्वाहिश है जो मेरे परिवार का तथा मेरा आदर करे.

—**श्रीदेवी,** *दैनिक जागरण*

• अगर आप कहें कि औसत पुरुष हर तीसरे मिनट सेक्स के बारे में सोचता है तो मैं कहूंगी कि तब मैं औसत किस्म के पुरुष को कतई पसंद नहीं करती.

■ **सोनू वालिया,** *स्टारडस्ट*

• हमारे दल के नेता के.पी. सिंहदेव ने हमारा अपमान किया, हमें यह कहा कि हम यहां सरकार की मेहरबानी से आ सके हैं. उन्होंने वंदना राव से कहा कि तुम्हारे मां-बाप ने तुम्हें ठीक से क्यों नहीं पाला.

■ **अश्विनी नायप्पा** (सिओल में), *इंडियन एक्सप्रेस*

भरिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडें लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूं.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

Walt Disney
डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रफादफा नहीं होगा

● सरकार उम्मीद लगाए बैठी थी कि वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों की विवादास्पद खरीद का मामला जल्दी ही रफादफा हो जाएगा. पर लगता है कि संघमित्रा गुप्ता इन उम्मीदों पर पानी फेरने जा रही हैं. 14 जुलाई के दिन उनके पति 48 वर्षीय तपन गुप्ता और बेटी 19 वर्षीया श्रीलेखा उनकी आंखों के

सभी कार्टून: अजीत नैनन

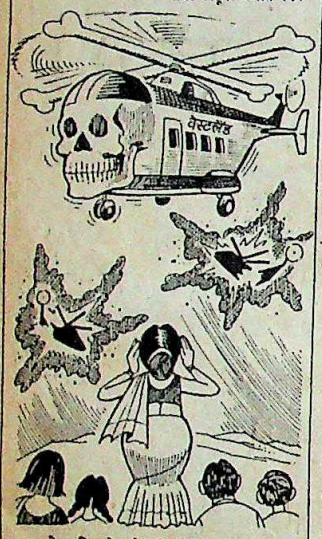

सामने ही वैष्णो देवी के पंछी-व्यू हेलिपैड पर हुई एक पवनहंस दुर्घटना में मारे गए थे.

प्रमुख संसद सदस्यों को लिखे पत्र में संघमित्रा ने मांग की है कि इस मामले की नए सिरे से जांच कराई जाए. उन्होंने लिखा है, "सवाल यह उठता है कि पहले से ही घटिया साबित हो चुके हेलिकॉप्टर के परीक्षण के लिए इंसानी जिंदगियों को क्यों इस्तेमाल किया गया?"

संघमित्रा ने इस हेलिकॉप्टर की कार्यप्रणाली और इतिहास के बारे में व्यापक अध्ययन किया है. अंतरराष्ट्रीय उड़ान नियमों और वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर की सुरक्षा और मौसम संबंधी तथ्यों का खासा अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि इस हेलिकॉप्टर में कबाड़ा हो चुके पंखे, घटिया दर्जे के क्लच-ड्रम, तेल के रिसने और इंजन की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के फेल होने जैसी कई खराबियां हैं. पत्र में उन्होंने लिखा है, "अमेरिका में इन हेलिकॉप्टरों की उड़ान पर पूरी तरह पाबंदी है. फिर भारत में इस तरह के हेलिकॉप्टरों को किस आधार पर शामिल किया गया?" ठीक यही सवाल उठाते हुए कई सांसदों ने प्रधानमंत्री से एक पत्र में मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से कराई जाए.

फिर लौटेंगे दिल्ली

● राजधानी के सत्ता गलियारों में इन दिनों चर्चा का केंद्र जगमोहन बने हुए हैं. खबर गरम है कि जम्मू-कश्मीर की जनता के दिलों पर धाक जमाने वाले जगमोहन नवंबर में राज्यपाल का अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाए जा रहे हैं. घाटी में कट्टरतावादी तत्वों पर काबू पाने, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और चरस की खेती पर रोक लगाने जैसे कदमों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था.

लेकिन उनका हटाया जाना इस कारण नहीं कि केंद्र उनसे नाराज है बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वालों ने यह दलील पेश की है कि आने वाले चुनावों में अगर इंका की गिरती साख को बचाना है तो जगमोहन को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए. उधर, आलाकमान ने भी जगमोहन से राय मांगी है कि क्या वे शहरी विकास मंत्रालय

संभालना चाहेंगे. लेकिन इंका नेताओं का दूसरा वर्ग भी है जो मानता है कि कश्मीर में अस्थिरता का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है. लिहाजा स्थिति को संभालने के लिए जगमोहन को वहीं रखा जाए. जगमोहन की लोकप्रियता केंद्र में भुनवाई जाए या जम्मू-कश्मीर में, इसका फैसला नवंबर तक हो जाने की पूरी उम्मीद है.

उम्मीद अभी बाकी

● इधर पिछले कुछ दिनों से साउथ ब्लॉक और फ्रांसीसी दूतावास के बीच दौड़ लगाने वाली कारों और अफसरों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हो गई है. खुद प्रधानमंत्री की इच्छा पर भारतीय अधिकारी फ्रांस सरकार से मांग कर रहे हैं कि आगामी फरवरी से शुरू होने वाले फ्रांस महोत्सव के लिए वह

कुछ बेहतर चीजें भारत भेजे. समारोह का उद्घाटन बंबई में चौपाटी पर लेसर टेक्नॉलोजी वाले एक विशाल कार्यक्रम से होने वाला है.

फ्रांस महोत्सव के सिलसिले में एक बड़े अधिकारी ने तो पत्र लिखकर यह आरोप भी लगा डाला कि फ्रांस सरकार अपने वायदों से मुकर रही है. बताया जाता है कि वायदे के मुताबिक फ्रांसीसी इतिहास से जुड़ी कई कांस्य मूर्तियां इस समारोह के लिए भारत भेजी जानी थीं. 1985 में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जैक्यूज शिराक ने तो मोनालिज़ा की पेंटिंग भेजने की भी संभावना व्यक्त की थी. लेकिन पेंटिंग पर हुए हमले को देखते हुए अब इसे बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी गई है.

दिल्ली के कला क्षेत्रों के कुछ धुरंधर फ्रांस सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वह अपनी कुछ ऐतिहासिक विरासतों की प्रदर्शनियां भी भारत भेजेगी. भारत ने भी अपने 1985 वाले भारत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट ऐतिहासिक चीजें फ्रांस भेजी थीं. हाल ही में हुए सोवियत महोत्सव में रूस के उत्साह को देखते हुए पेरिस सरकार से भी ऐसे ही उत्साह की उम्मीद पूरी होती भले ही न दिखे पर यह उत्साह बेमानी नहीं.

इंतजार और अभी

● कस्टम विभाग के अधिकारी तीन साल से वह सरकारी वायदा पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं जो तत्कालीन वित्तमंत्री और अब जनमोर्चा नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था. ईमानदार कस्टम अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने पकड़े गए सोने व दूसरे माल की कीमत का एक हिस्सा इनाम के तौर पर देने और एक हिस्से से उनके लिए कल्याण कोष बनाने की योजना चलाई थी.

इनाम की चर्चा तो देश भर में हुई पर योजना का एक आश्वासन अभी भी अमल के लिए सरकारी फाइलों में कलाबाजियां खा रहा है. योजना में विभाग के कर्मचारियों के लिए पहाड़ी इलाकों में आरामदेह गेस्ट हाउस बनाने की बात भी शामिल थी. लेकिन इस कोष में अब तक 15 करोड़ रुपए जमा होने के बावजूद इनका कहीं अता-पता नहीं.

अब मंत्रालय के बड़े अफसरों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पैसे से गेस्ट हाउस बनाने के बजाय इसका उपयोग वायरलेस सेट और आधुनिक किश्तियों जैसी जरूरी चीजें खरीदने में किया जाएगा. जब तक गेस्ट हाउसों की बारी नहीं आती तब तक बेचारे अफसरों को अपनी इनाम राशि में से ही होटलों के बिल भुगतान करने पड़ेंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शालें

जिनमें छलके मुग़लों की आन-बान सदियों की शान और प्राकृतिक अद्‌भुतता!

पश्मीना, शाहतूश, जामावार...

पसंद : आपकी। स्थान : आहूजासंस

आहूजासंस शालों की दुनिया की वैभवशाली परम्पराओं को आपके सम्मुख गर्व से प्रस्तुत करते हैं।
शालें जो सम्राटों, नरेशों और नवाबों की मनमोहक सज्जा की प्रतीक रही है। शालें जो प्रकृति की उत्कृष्ट कला तथा रंगों को दर्शाती हैं – जिनके प्रत्येक धागे में पिरोया गया है – वैभव तथा सौंदर्य।

TRENDS-AS-1438

आहूजासंस – जिनके लिए शाल कोई व्यापारिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक गौरवपूर्ण परम्परा है।

आहूजासंस
शाल वाले (प्रा०) लि०

6/44, अजमल खां रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110 005, फोन : 5720304, 583154

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नौकरी और छोकरी

■ किसी दिन अचानक यह घोषणा हो जाए कि हर बेरोजगार को नौकरी के साथ-साथ छोकरी, यानी बीवी भी मिलेगी तो क्या होगा? शायद वही होगा जो पिछले पखवाड़े उत्तर प्रदेश के

सभी कार्टून: मंजुला पद्मनाभन

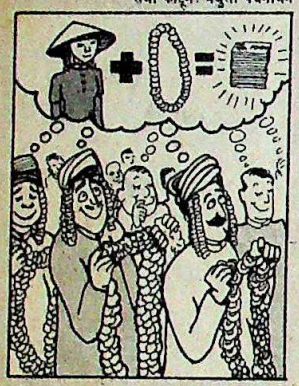

मिर्जापुर इलाके में हुआ. देखते ही देखते वहां के रोजगार कार्यालयों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गईं; पंजीकरण फार्म मुंहमांगे दामों पर बिकने लगे और नेताओं, अफसरों और यहां तक कि स्थानीय पत्रकारों के घरों में भी सिफारिशी चिट्ठियों के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई.

किस्से की शुरुआत इस खबर से हुई कि वियतनाम में पुरुषों की कमी को देखते हुए वहां की सरकार ने फैसला किया है कि वियतनामी युवतियों को शादी के लिए भारत भेजा जाए. शादी योग्य चुने गए उम्मीदवार दूल्हों को वहां की सरकार की ओर से हर महीने 5 हजार रुपए भत्ता और बेटा पैदा होने पर 25 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा. शर्त बस इतनी कि दूल्हे मियां का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए. कुछ दिनों में ही खबर की दूसरी किस्त आई कि वियतनामी युवतियों का पहला दल जल्दी ही मिर्जापुर पहुंच रहा है. रोजगार दफ्तरों पर बढ़ती भीड़ और सिफारिशी लोगों से परेशान नेताओं व अफसरों की शिकायतों के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों को बहुतेरे यह समझाने की कोशिश की कि यह सब अफवाह है, पर लोग थे कि इन खंडनों को ही अफवाह मान कतारों की लंबाई बढ़ाते रहे.

बंदर का बदला

■ बिहार का भागलपुर शहर इन दिनों एक ऐसे बंदर के आतंक से त्रस्त है जो एक खास सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल चालकों पर हमले करता है. यह बंदर अब तक लगभग दो सौ मोटरसाइकिल चालकों पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर चुका है. हैरानी की बात यह है कि स्कूटर और मोपेड चालक उसके गुस्से का शिकार नहीं होते.

भागलपुर-सबौर मार्ग पर इस आतंक से मोटरसाइकिल चालकों को मुक्ति दिलाने के अब तक के सारे प्रयास असफल रहे हैं. बताया जाता है कि बंदर को पकड़ने के लिए स्थानीय वन विभाग कई बार अलग-अलग तरीके अपना चुका है पर बंदर है कि उनके झांसे में आने का नाम ही नहीं लेता. उसे पकड़ने या दूर भगाने के लिए पुलिस विभाग भी कई कोशिशें कर चुका है पर उनका असर नहीं हुआ. उलटे अब हालत यह है कि वह किसी खाकी वर्दी वाले को देखते ही उस पर झपटने लगा है. नतीजा यह हुआ है कि न केवल मोटरसाइकिल चालक और पुलिस कर्मचारियों ने बल्कि दूसरे विभागों के वर्दीधारी कर्मचारियों ने भी अपना रास्ता बदल लिया है. हालांकि कुछ अधिकारी बंदर को गोली मारने या जहर देने के पक्ष में हैं पर धर्मभीरु कर्मचारियों में से कोई

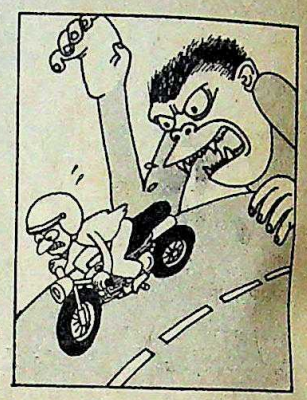

भी यह कदम उठाने को तैयार नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक मादा बंदर एक मोटरसाइकिल के नीचे कुचली गई थी. बंदर शायद इसी कारण मोटरसाइकिल चालकों से नाराज है.

जिंदा या मुर्दा

■ जिला मजिस्ट्रेट की अदालतों में ऐसे मामले आए दिन आते रहते हैं जिनमें किसी मृतक के परिवार के लोग उसका मृत्यु प्रमाणपत्र लेना चाहते हैं. लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक

मजिस्ट्रेट तब सकते की हालत में आ गए जब सरकारी फाइलों में 'मुर्दा' घोषित हो चुके एक व्यक्ति ने उनके सामने यह मांग पेश कर दी कि उसे 'जिंदा' होने का प्रमाणपत्र जारी किया जाए. जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अपनी तरह का अनूठा मामला था.

किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मजिस्ट्रेट ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की. पता चला कि वसंत कुबल का नाम दो साल पहले किसी भूमि विवाद में शामिल था. इस विवाद के सिलसिले में जब अदालत ने उसके नाम सम्मन जारी किया तो उसके गांव के पटवारी ने इसे इस टिप्पणी के साथ वापस भेज दिया कि वसंत दो साल पहले ही मर चुका है. नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों में ही वसंत को कई सरकारी फाइलों में मृतक घोषित कर दिया गया. अपनी 'मौत' की यह खबर जब वसंत तक पहुंची तो उसने दौड़-धूप शुरू की लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसकी नहीं सुनी. आखिर सब ओर से निराश होकर उसने तहसील के मजिस्ट्रेट के यहां हाजिर होने और खुद को 'जिंदा' घोषित करवाने का फैसला किया. आखिरी समाचार आने तक स्थानीय पुलिस वसंत की जांच करके यह तय करने में लगी हुई थी कि वह सचमुच जिंदा है भी या नहीं.

फोन नाम सत्य है

■ हिंदुस्तानी टेलीफोन विभाग की मेहरबानी से आज कम-से-कम शहरों और कस्बों में तो टेलीफोन आम आदमी की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन ही चुका है. इस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भले ही फोन काम करे या न करे; भले ही वह इस हद तक खराब हो जाए कि गलत नंबर मिलाने पर भी ठीक नंबर मिल जाए और भले ही उसमें से डायल टोन के बजाय विविध-भारती का विज्ञापन कार्यक्रम बजता रहे—बेचारे उपभोक्ता नियम से किराए के अलावा उन कॉलों का भी भुगतान करते रहते हैं जो नियमानुसार 'रांग नंबर' अधिक होतीं हैं और सही कम. विश्वास यही रहता है कि कभी न कभी तो फोन सही काम करेगा ही.

लेकिन अगर यह विश्वास भी टूट जाए तो? तो वही होगा जो पिछले दिनों कानपुर में हुआ. स्थानीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने फोन सेवा की खराब हालत पर विरोध प्रकट करने का नया नुस्खा ढूंढ़ निकाला. लकड़ी का एक विशालकाय टेलीफोन बनवाया गया जो असली टेलीफोन की तरह खूबसूरत और एकदम 'डेड' था. इस 'डेड' फोन की शानदार अर्थी सजाई गई और 'राम नाम सत्य है' की गूंज के बीच शहर भर में शवयात्रा निकाली गई. बाद में

टेलीफोन एक्सचेंज के सामने शहर के व्यापारियों ने अपने प्यारे दिवंगत फोन को श्रद्धांजलियां पेश की और मंत्रोच्चार के बीच फोन का दाह-संस्कार किया गया.

संकलन—विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तेज धड़कनों का सबब

वक्त की धड़कनें जैसे अचानक ही तेज हो गईं पिछले पखवाड़े. लगा जैसे अचानक ही उन्हें कोई नई ऊर्जा, कोई मकसद मिल गया हो. देश के राजनैतिक क्षितिज पर चुनाव के जो बादल मंडराने लगे हैं या दूर कहीं से उसके नगाड़ों की जो आवाज आने लगी है, लगता है, यही सबब है इन तेज धड़कनों का.

और सत्ता के रणबांकुरे अपने हथियारों पर सान चढ़ाने लगे हैं. जल्दी ही पैदल सेनाएं अपने-अपने नायकों के नेतृत्व में चारों ओर फैल जाएंगी—झोंपड़ियों से लेकर बंजर इलाकों तक. चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है, उसकी आवाज सुनाई देने भी लगी है.

शायद यह संयोग मात्र नहीं है कि सत्य बनाम असत्य के 'महाभारत' की अमर कथा हर हफ्ते देश भर के टेलीविजन सेटों के परदों पर जीवंत होने लगी है.

आगामी चुनाव भी, चाहे समय से पहले हों या समय पर, देश की आजादी के बाद का संभवतः सबसे महान राजनैतिक संघर्ष सिद्ध होगा. पहले कभी इतना कुछ एक साथ दांव पर नहीं लगा और न विकल्प कभी इतने लचर रहे. एक ओर विपक्षी एकता का प्रहसन अपने दुखद उपसंहार की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपनी गिरती साख को संभालने की जीतोड़ कोशिशों में लगा है. एक ओर है आपसी अनबन में फंसे 'आदर्शवादियों' की जमात तो दूसरी ओर है समझौतों और सनक से त्रस्त दल. और मतदाता की नियति है द्वंद्व और दुविधा में दोहरे होते रहना.

चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं लेकिन दोनों खेमों में जो अफरातफरी दिख रही है उससे यही उजागर होता है कि उन्हें अपनी साख और वक्त के तेजी से घटते जाने का एहसास होने लगा है. विपक्ष अपनी मोर्चाबंदी में जितना वक्त गंवाएगा, उसकी संभावनाएं उतनी ही धूमिल होती जाएंगी. विडंबना यह है कि दोनों खेमों की कमजोरियां ऊपर से तो भिन्न दिखती हैं मगर वास्तव में हैं समान ही.

विपक्ष की मुश्किल यह है कि इसके खेमे में नायकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है और उनके अहं भी जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हैं. इसके एक नायक जिसकी थोड़ी साख है, वह हैं—वि. प्र. सिंह. मगर वे भी जिम्मेदारियों से भागते ही नजर आते हैं. सत्ता दल की लोकप्रियता और उसका भविष्य भी इसके नायक—राजीव गांधी—पर ही टिका है.

दूरदर्शन महानिदेशक की अचानक बरखास्तगी और इसके बाद दूरदर्शन के समाचारों में राजीव गांधी के छाते जाने से साफ है कि पूरा मामला चुनावी नफा-नुकसान के हिसाब-किताब का था. टेलीविजन अब सत्ता दल का मुख्य प्रचारक बन जाएगा. इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है. कुछ मिसाल:—टीवी परदे पर दिखने वाले मंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी, गिरफ्तार आतंकवादियों से बातचीत का प्रसारण, गोरखालैंड कार्यकर्ताओं का हथियार समर्पण, श्रीलंका में भारतीय भूमिका और संदेहास्पद उपलब्धियों का बखान.

और राजीव गांधी जिस तरह से तमिलनाडु, पंजाब और काशीपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं उससे भी चुनावी मंशा का पता चलता है. और दुख की बात तो यह है कि सलमान रुशदी की किताब पर पाबंदी भी इसी मंशा का परिचय देता है.

लेकिन तमाम वायदों और समझौतों के बावजूद कहीं कुछ बदलने की उम्मीद नहीं दिखती. विपक्ष आज एक होकर कल बिखर सकता है, राजीव और उनकी पार्टी आज वायदे करके कल मुकर सकती है. यानी कुल मिलाकर फैसला इस बात का करना रह जाएगा कि कौन कम बुरा है.

—दिलीप बॉब

चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है. उसकी आवाज सुनाई भी देने लगी है

पहले कभी इतना कुछ एक साथ दांव पर नहीं लगा और न विकल्प कभी इतने लचर रहे

कार्टून: अजीत नैनन

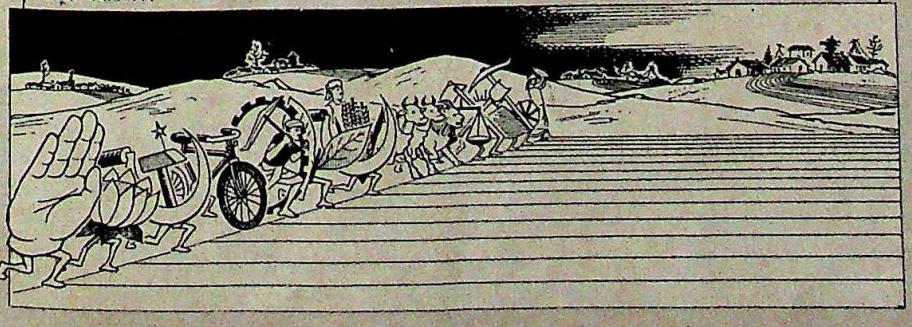

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

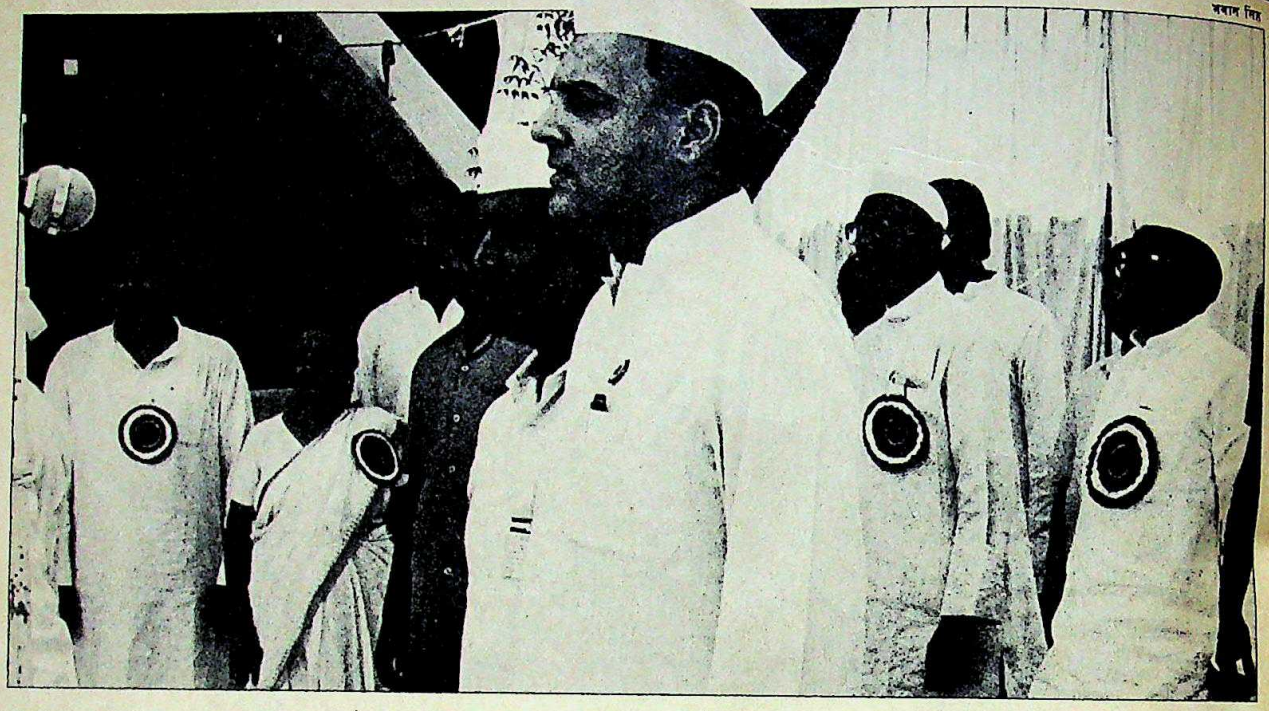

कांग्रेस (इ)

कमर कसने की कसरत

विपक्षी पार्टियां अगर एकता के अपने प्रयासों की वजह से हर रोज सुर्खियों में बनी हुई हैं, तो इंका भी कोई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है. चुनाव के दिन जैसे-जैसे नजदीक आते दिख रहे हैं, वह भी अपनी कमर कसने लगी है. चुपचाप मगर नियमित रूप से वह ढीले पड़ गए अपने संगठन को कसने में लग गई है. कार्यकारी संपादक इंद्रजीत बधवार और वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला इंका की अंदरूनी गतिविधियों का जायजा ले रहे हैं:

नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग के उस पुराने सरकारी बंगले का माहौल रातोरात बदल गया है. अचानक ही गतिविधियां तेज हो गई हैं. आशुलिपिकों की उंगलियां टाइप मशीनों पर तेजी से दौड़ने लगी हैं. ऐसे दस्तावेजों की आमद-रफ्त बढ़ गई है जिन पर 'गोपनीय' का ठप्पा लगा होता है. पार्टी सांसदों का जमावड़ा भी इधर एकदम बढ़ गया है.

यह जगह अब आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों की तैयारी का केंद्र बन गई है. जाहिरा तौर पर तो यह बंगला इंका की नीति व कार्यक्रम समिति का दफ्तर है मगर यह प्रधानमंत्री का मिनी राजनैतिक सचिवालय बन गया है. उक्त समिति का काम है—निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना. यह इंका का नया मंत्र है. समिति के अध्यक्ष और पार्टी महासचिव विट्ठल नरहरि गाडगिल के अनुसार, "हमारा मुख्य काम है चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न तबकों के पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के विचार इकट्ठा करना." महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह कहते हैं, "असल में हमारा काम है मुद्दों को पहचानना, जानकारियों को स्थानीय इकाइयों तक भेजना, फिर उनसे जानकारियां इकट्ठी करके उन्हें प्रधानमंत्री व कांग्रेस कार्यकारिणी तक पहुंचाना."

अब कोई भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी और उनकी पार्टी को एक और संगठन की क्या जरूरत पड़ गई जबकि नौकरशाही और दूसरी एजेंसियां पहले से ही उनके लिए भाग-दौड़ कर रही हैं? दरअसल, राजीव चाहते हैं कि चुनाव से पहले की यह अहम कसरत पार्टी के ढांचे से बाहर ही की जाए. पार्टी के दिग्गज साफ तौर पर मानते हैं कि विपक्षी एकता प्रयासों के चलते इंका के हाथ-पांव फूल गए हैं. कई जनमत सर्वेक्षणों से साफ है कि इसकी लोकप्रियता में कमी आई है. उम्मीद है कि दिसंबर तक संसदीय उम्मीदवारों की सूची तैयार हो जाएगी और उन्हें चुपचाप चुनाव प्रचार शुरू कर देने को कह दिया जाएगा. चुनाव घोषणापत्र का खाका और एक प्रभावशाली नारा (1980 के 'चुनिए उन्हें जो सरकार चला सकें' की तर्ज पर) तैयार हो जाने की भी उम्मीद है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राजीव: जड़ों की मजबूती

और अब जब पार्टी ने प्रचार अभियान के लिए आस्तीनें चढ़ा ली हैं, एक उच्चस्तरीय सलाहकार समिति भी बस बनने ही वाली है. यह समिति चुनाव के माहौल में गूंजने वाले आकर्षक जुमले और लच्छेदार नारे बनाएगी. प्रधानमंत्री के ये मुट्ठी भर सलाहकार पार्टी के वे सदस्य होंगे जिनकी प्रधानमंत्री तक अच्छी पहुंच है. और इन सबकी अगुआई करेंगे प्रधानमंत्री के खासमखास कैप्टन सतीश शर्मा. समिति के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रधानमंत्री के दून स्कूल के दोस्त रोमी खोना, बंबई की विज्ञापन एजेंसी 'रीडिफ्यूजन' के अरुण नंदा, प्रधानमंत्री के दूर-पार बाजीगर सैम पित्रोदा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री शीला दीक्षित.

आगामी चुनाव के कुछ पैमाने तय कर लिए गए हैं. और, जोर असंतुष्ट पार्टीवालों को साथ लेकर पार्टी के काम में निचले स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बनाने पर होगा, पार्टी में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े लोगों के झगड़े शांत किए जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की कोशिश होगी और 20 सूत्री कार्यक्रम में सुधार किया जाएगा.

इनमें सबसे अहम तत्व है 'सुधार'. पार्टी का यह नया 'ढांचा' चुनाव के लिए समर्पित होगा. चूंकि लक्ष्य वोट और सत्ता है, ये सुधार कोई परमार्थ साधने के लिए नहीं होंगे. इसलिए मंशा राजनैतिक माहौल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की है. यह महज इत्तफाक ही होगा कि कहीं-कहीं पार्टी के हित आम जनता के हितों से मेल खा जाते हों. लेकिन बिहार प्रदेश इंका के नौजवान अध्यक्ष तारिक अनवर कहते हैं, "सिर्फ कांग्रेस ही सोचती है कि पूरे देश का भला किस बात में है. और, बदलाव लाने के लिए इसके पास पूरा सरंजाम है."

मिसाल के लिए चुनाव सुधारों का वक्त आ गया है. इसे सबसे जोरदार ढंग से जनमोर्चा नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह उठा रहे हैं. इस मामले में वे शासक दल से आगे निकल गए हैं. राजनीति को पैसे से अलग करने की उनकी गुहार में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विपक्ष की मांग भी जुड़ गई है. इंका अभी तक इस मुद्दे से अपना दामन बचाती ही रही है. पर अब यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा. पार्टी के इन आला हितचिंतकों ने एक नया रास्ता निकाला है. वे चुनाव सुधारों के कुछ ऐसे प्रस्ताव तैयार करेंगे जो पार्टी के लिए फायदेमंद हों, और विपक्ष की मांग को फीका कर दें. विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह इसे पार्टी का मौलिक सोच बताते हैं, "हम जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं उन्हें पार्टी के निचले स्तर के कार्यकताओं ने सेमिनारों में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उठाया है."

चुनाव सुधार का यह घोषणापत्र अब तैयारी के आखिरी दौर में है. उम्मीद है कि इससे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग को सिरे से ठुकरा दिया जाएगा, बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की सिफारिश की जाएगी और चुनाव प्रचार का समय कम करने की मांग की अनदेखी की जाएगी. और सरकारी खर्च से चुनाव लड़ने के प्रावधान की मांग को— जिसे वी.पी. सिंह उठाते रहे हैं— अव्यावहारिक बताया जाएगा. पार्टी संसदीय चुनाव के खर्च की सीमा प्रति सीट 1.5 लाख रु. को रद्द करने के पक्ष में है. अन्य सिफारिशें हैं:

► लोगों को वोट डालने के अयोग्य ठहराने का काम चुनाव अधिकारी का हो. ऐसे लोग तुरंत ही फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करा सकेंगे. सभी मुख्य चुनाव अधिकारी दूसरे प्रदेशों के हों.

► हर उम्मीदवार को 12 से 16 मतदाता सूचियां दी जाएं, उन्हें पेट्रोल भी दिया जाए और छपाई की सुविधाएं भी. उन्हें सभाओं के लिए सरकारी स्कूलों व खेल के मैदानों के इस्तेमाल की इजाजत भी मिले. उन्हें अपना प्रचार साहित्य कम-से-कम एक बार डाक से मुफ्त भेजने की सुविधा मिले. मतदाताओं को उनकी पहचान पर्ची और एक नमूना मतपत्र डाक से भेजा जाए.

ये प्रस्ताव बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं पर वी.पी. सिंह का कहना है, "हमें तो यह आंखों में धूल झोंकने की तरह लगता है. सारी

चुनाव की रणनीति और नारे तय करने के लिए आलाकमान के विश्वासपात्रों की एक नई उच्चस्तरीय सलाहकार समिति गठित होने ही वाली है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खराबी की जड़ है पैसे और राजनीति का गठजोड़. इसे छुआ तक नहीं गया.'' कई लोगों को लगता है कि इनका फायदा शासक दल को ही मिलेगा. डाक से प्रचार साहित्य भेजने के मामले में तो नौकरशाही सत्ता पक्ष की तरफदारी को मजबूर होगी.

विपक्ष इसी तरह विकेंद्रीकरण के सवाल पर भी इंका की हवा खराब करने पर आमादा दिखता है. वह अरसे से स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने और पंचायती-राज व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहा है. यह संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा भी है. अब इंका इसी हथियार से विपक्ष पर हल्ला बोलने जा रही है. उसे अब इसी की जरूरत है.

हाल ही में पार्टी के सेमिनारों और तूफानी अधिवेशनों में एक बात स्पष्ट हो गई कि पार्टी इस कदर केंद्रित हो गई है कि राज्य और जिला स्तर पर उसका धंधा ही चौपट हो गया है. इंका के घोषणापत्र की मुख्य मंगा है नगरपालिका, प्रमुख और प्रधान स्तर के चुनाव करवाकर अपनी ताकत का अंदाज लगाना और अपने समर्थकों को इन पदों पर बिठाना. वह जिला परिषदों को भी पुनर्जीवित करना चाहती है. ज्यादातर इंका शासित राज्यों में एक दशक से इनके चुनाव ही नही हुए.

पर जिला परिषदों के चुनाव निकट भविष्य में नहीं होने हैं क्योंकि तबाहीखेज नतीजों की आशंका और इसमें होने वाले खर्च को देखते हुए यह मुश्किल ही दिखता है. पर पार्टी उनमें फिर से जान फूंकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाएगी. ये परिषदें सांसदों और विधायकों की बिरादरी में काफी बदनाम रही हैं क्योंकि जिला स्तर पर ये सत्ता के प्रतिस्पर्धी केंद्र का काम करती हैं.

पर इंका के सेमिनारों में इस बात का भी जिक्र हुआ कि निचले स्तर की भागीदारी जल्द ही निचले स्तर पर मिलने वाले संरक्षण पर निर्भर है. इसलिए इसकी बागडोर स्थानीय स्तर पर निर्वाचित पदाधिकारियों के हाथ ही होनी चाहिए. जिला परिषदों को ज्यादा अधिकार देने की हिमायत करने वाले इंका के इस घोषणापत्र में शायद आईएएस व पीसीएस अफसरों के महत्वपूर्ण अधिकार छीनकर उन्हें परिषदों व स्थानीय राजनीतिकों को सौंप देने का वादा भी होगा.

इस कसरत का मुख्य मकसद है स्थानीय प्रशासन को स्थानीय राजनीतिकों की प्रभावी निगरानी में लाना. इस विकेंद्रीकरण का सबक दरअसल इलाहाबाद उपचुनाव से मिला है जिसमें अधिकारियों ने इंका उम्मीदवार के हक में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से इनकार कर दिया था. नए प्रस्ताव के तहत जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के बारे में गोपनीय रिपोर्ट अब मंत्री या मंडल आयुक्त के बदले परिषद के अध्यक्ष लिखेंगे.

बीस सूत्री कार्यक्रम में 'सुधार' (जिसकी विपक्ष समेत तकरीबन हर कोई मांग कर रहा है) के नाम पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं की समीक्षा भी जिला परिषद ही करेगी. इसका घोषित मकसद उस भ्रष्टाचार से निजात पाना है जो कार्यक्रम के गरीब जनता तक पहुंचने से पहले ही उसकी जड़ खोद देता है. पर विपक्ष के एक कट्टर समर्थक का कहना है, ''यह सब चालाकी है. उन्होंने विपक्ष के तीन खास मुद्दों— चुनाव सुधार, विकेंद्रीकरण और गरीबी हटाने की योजनाओं में से भ्रष्टाचार को उठा लिया और उसे इंका के कार्यक्रम में मिलाकर पेश कर दिया. पर इस फेरबदल से इंका को ही फायदा मिलेगा यानी सिर्फ बिचौलिए बदले जाएंगे.''

लेकिन वजह और राजनैतिक मंशा जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि इंका राज्य और स्थानीय स्तर से रिश्ते गांठने के लिए दिल्ली से बाहर निकल रही है. इसकी पहल खुद प्रधानमंत्री ने की है. उम्मीद है कि चीन यात्रा के तुरंत बाद वे पार्टी असंतुष्टों से बात करने के लिए पूरे राष्ट्र का तूफानी दौरा करेंगे. उनके एक सलाहकार के अनुसार ''इन असंतुष्ट इंकाइयों को लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में वे पार्टी व राजनैतिक प्रक्रिया से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए हैं.'' उन्हें वापस बुलाने के लिए प्रधानमंत्री खुद अपने व्यक्तिगत असर का इस्तेमाल करेंगे. उम्मीद है कि इलाके के सांसद और विधायक की मौजूदगी में गांवों में सभाएं होंगी, और

विश्वासपात्र माने जाने वाले नौकरशाह अब उन मंत्रियों की गतिविधियों का जायजा लेने लगे हैं जिन्हें सत्ता पार्टी के संगठन को चुस्त बनाने का काम सौंपा गया है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

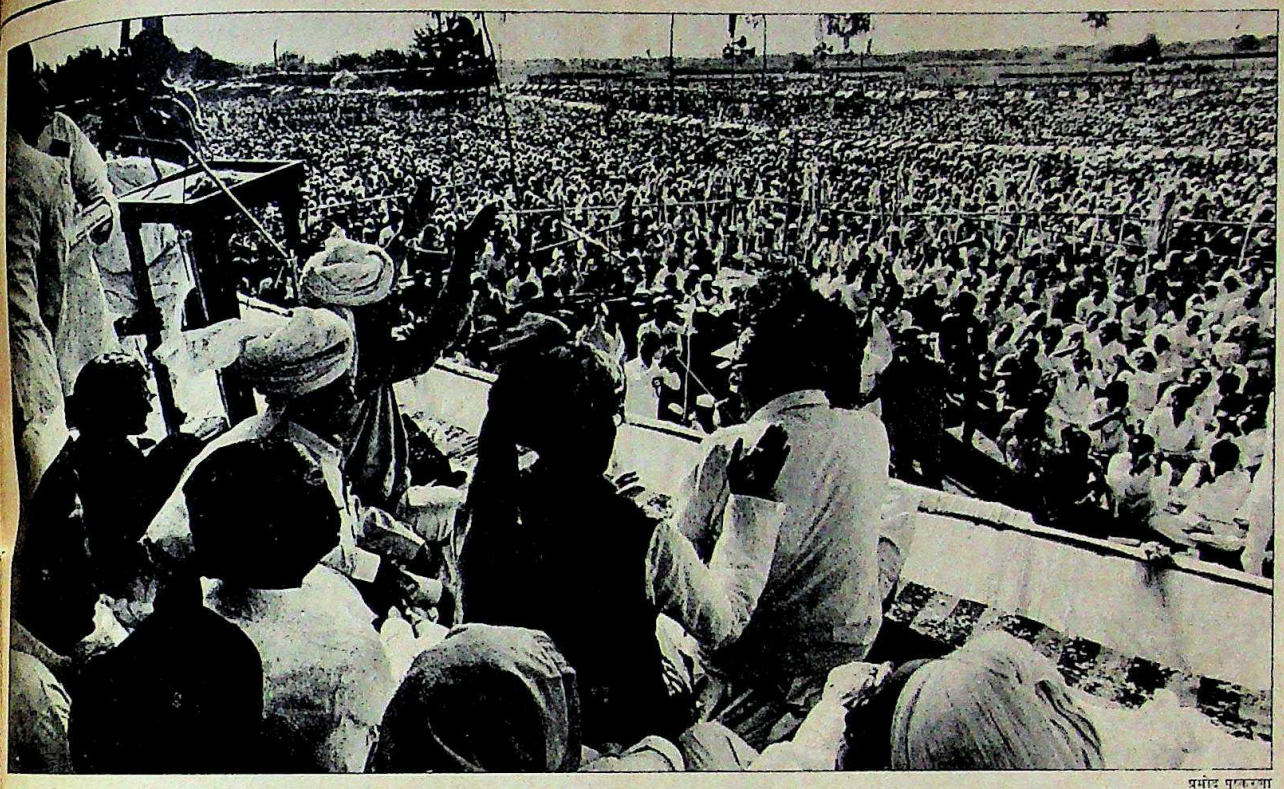

प्रमोद पुष्करणा

चुनाव से पहले इंका महासमिति द्वारा पार्टी के चार लंबे अधिवेशन किए जाएंगे.

असंतुष्टों को मनाने की कोशिशें तो शुरू भी हो गई हैं. पार्टी आलाकमान ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि मंडी समितियों और सहकारी संस्थाओं में उन्हीं इंकाइयों को मनोनीत किया जाए जो पहले किनारे लगा दिए गए थे. उन्हें राशन की दुकानों, मिट्टी के तेल व बीजों की बिक्री की दुकान खोलने की मंजूरी देने में प्राथमिकता दी जाएगी.

व्यापक रणनीति के तहत पार्टी अलंबरदारों के झगड़े निबटाने के लिए राजीव अब पंच की भूमिका निभाएंगे. वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और उनके प्रबल विरोधी केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा के बीच हुई 45 मिनट की समझौता वार्ता की अध्यक्षता भी कर चुके हैं. वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी व केंद्रीय मंत्री वीर बहादुर सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार व पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले, ओडीसा के मुख्यमंत्री जे.बी. पटनायक व पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी के बीच भी यही भूमिका निभाएंगे.

गैर-इंकाशासित राज्यों पर राजनैतिक हल्ला बोलने की नीति जारी रहेगी ताकि विपक्ष के लिए प्रचार करके राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश करने वाले मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेश में ही सीमित रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए. इंका ने अब आंध्र

हरियाणा में गूजरों की रैली में इंका नेता: जातिवादी राजनीति का सहारा

प्रदेश में नंदमूरि तारक रामराव, केरल में ई.के. नयनार और बंगाल में ज्योति बसु के खिलाफ आंदोलन शुरू भी कर दिया है.

केंद्र ने गैर-इंकाशासित राज्यों को विकास और राहत कोष से पैसा देने के मामले में राजनीति खेलनी शुरू कर दी है. पश्चिम बंगाल की बक्रेश्वर विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तेलुगु गंगा परियोजना इसकी मिसाल है. असम और हरियाणा जैसे राज्य लगातार यह शिकायत कर रहे हैं कि उनके राज्य में सूखे से हुई तबाही का मुकाबला करने के लिए केंद्र ने पर्याप्त मदद नहीं की.

बाढ़ आई हो या न आई हो, पर गैर-इंकाशासित राज्यों पर दबाव बढ़ने की ही उम्मीद है. पहला निशाना हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में राज्य से इंका का सफाया कर दिया था. पिछड़ी जातियों में थोड़ी-बहुत साख रखने वाले केंद्रीय भूतल परिवहनमंत्री राजेश पायलट को हरियाणा का मोर्चा संभालने के लिए चुना गया है.

प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों ने पार्टी के अति महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया है—काम करने वाले और निगरानी करने वाले. पायलट की तरह के नेताओं के असर और गतिविधियों का राजीव अब नियमित जायजा लेते हैं. इसके लिए वे केंद्रीय इस्पात व खानमंत्री माखनलाल फोतेदार, रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत, गृहमंत्री बूटा सिंह, शीला दीक्षित जैसे मंत्रियों की मदद लेते हैं.

पर राजीव यहीं नहीं रुक गए हैं. उन्होंने अपने आसपास अनौपचारिक सलाहकारों का भी गुट तैयार किया है जिसमें आईएएस स्तर के अधिकारी शामिल हैं. ये मंत्रियों के कामकाज का जायजा लेते हैं. इसमें प्रधानमंत्री की निजी सचिव सरला ग्रेवाल, सूचना व प्रसारण सचिव गोपी अरोड़ा, प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव मणि शंकर अय्यर, वित्त सचिव एस. वेंकिटरमनन, विशेष सचिव मोतेक सिंह अहलूवालिया शामिल हैं.

यह सब कुछ किसी बहुत बड़े अग्निशमन अभियान जैसा है जिसकी बागडोर खुद प्रधानमंत्री ने संभाली हुई है. पर यह अभियान तभी सफल हो सकता है जब लगातार हताश हो रहे वे इंका कार्यकर्ता भी इसमें जुट जाएं जो यह मानते हैं कि सिर्फ राजीव गांधी ही उन्हें चुनाव सागर के पार लगा सकते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकारों की सारी कोशिशों के बावजूद 1984 या 1985 का वह माहौल—जिसमें राजीव गांधी का नाम विजय का पर्याय बन गया था—फिर से बनता नहीं दिख रहा है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाममोर्चा

घटकों ने बजाई खतरे की घंटी

एक दशक से भी ज्यादा अरसे से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ वाममोर्चे में दरारें आने के संकेत मिल रहे हैं. वरिष्ठ संवाददाता ***कमलजीत रतन*** *स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य में मोर्चे के भविष्य का विश्लेषण भी कर रहे हैं. उनकी रिपोर्ट:*

ज्योति बसु पक्षपाती हैं. पता नहीं, मैं अब मंत्री रह पाऊं या नहीं.
—राज्य के कृषिमंत्री और फारवर्ड ब्लॉक नेता कमल गुहा

माकपा हमें स्टालिनवादी तरीके से खत्म करने पर आमादा है.
—राज्य के सिंचाईमंत्री और आरएसपी नेता देबब्रत बंद्योपाध्याय

प्रशासन मेरी सुनता ही नहीं. वह तो स्थानीय जिला माकपा सचिव को कहीं ज्यादा सम्मान देता है.
—राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्तिमंत्री तथा फारवर्ड ब्लॉक नेता निर्मल बोस

ज्योति बसु हठी, पक्षपाती और घमंडी हैं.
—राज्य के लोक निर्माणमंत्री और आरएसपी नेता जतीन चक्रवर्ती

यदि वाममोर्चा के साझीदार इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मोर्चे में उनके बने रहने का क्या औचित्य है?
—वाममोर्चा अध्यक्ष और राज्य माकपा सचिव सरोज मुखर्जी

पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा की स्थिति कलकत्ता की उस पुरानी ट्राम गाड़ी से मिलती-जुलती है जो जरूरत से ज्यादा मुसाफिरों के बोझ से चरमराती अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही हो.

माकपा की अगुआई वाले वाममोर्चे के 'मुसाफिरों'— फारवर्ड ब्लॉक और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी)— ने अपने वरिष्ठ साझीदार माकपा और उसके नेता मुख्यमंत्री ज्योति बसु के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला इधर तेज कर दिया है.

वाममोर्चे में दरार कुछ समय पहले ही दिखने लगी थी. लेकिन अब अपने वजूद के 11 साल बाद उसकी अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ जाने से शकुन अच्छे नहीं दिख रहे. मोर्चे के छोटे घटकों के नए तेवर की असल वजह तो और भी खतरनाक है. वह यह कि खुद बसु की महत्ता घटती जा रही है. बसु एक दशक से अधिक समय तक सरकार और मोर्चे पर छाए रहे. उनकी असंदिग्ध ईमानदारी ऐसे कवच का काम करती रही जिसे कोई भी आलोचना नहीं बेध पाई थी.

लेकिन अब ऐसी बात नहीं. माना जाने लगा है कि बसु अपने कामकाज में निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं. उनके आलोचकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो उन्हें खुलेआम घमंडी, अति-महत्वाकांक्षी और पार्टी के 'युवा तुर्कों' से घिरा बता रहे हैं. लेकिन हाल में बसु के खिलाफ भाई-भतीजावाद के जो आरोप लगे हैं, वह उनके झक सफेद धोती-कुर्ता पर सबसे बड़ा दाग है. मामला ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि ये आरोप उनके पुराने करीबी सहयोगी और आरएसपी नेता, 77 वर्षीय जतीन चक्रवर्ती ने लगाए हैं. उन्होंने बसु पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे चंदन बसु के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने की कोशिश की. चक्रवर्ती ने यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत भी पेश किए कि बसु ने अपने बेटे के हितों को बढ़ावा देने के लिए बंगाल लैंप्स वर्क्स लि. से भारी संख्या में फ्लोरेसेंट ट्यूब खरीदने पर जोर दिया था. 1979 तक चंदन बसु इसी कंपनी में थे.

आरोप से बिफर उठे बसु ने चक्रवर्ती को 'झूठा' करार देते हुए कहा कि उन्होंने चक्रवर्ती को बंगाल लैंप्स वर्क्स लि. या अपने बेटे के प्रति कोई विशेष रियायत बरतने के लिए कभी नहीं कहा था. लेकिन चक्रवर्ती अपनी बात पर अड़े रहे. उन्होंने जिस मौके पर यह आरोप लगाया, वह बसु और मोर्चे के लिए ज्यादा परेशानी वाली बात थी. मोर्चे के छोटे घटक पहले से ही विद्रोह पर उतारू हैं.

मुख्यमंत्री की छवि इन आरोपों से और

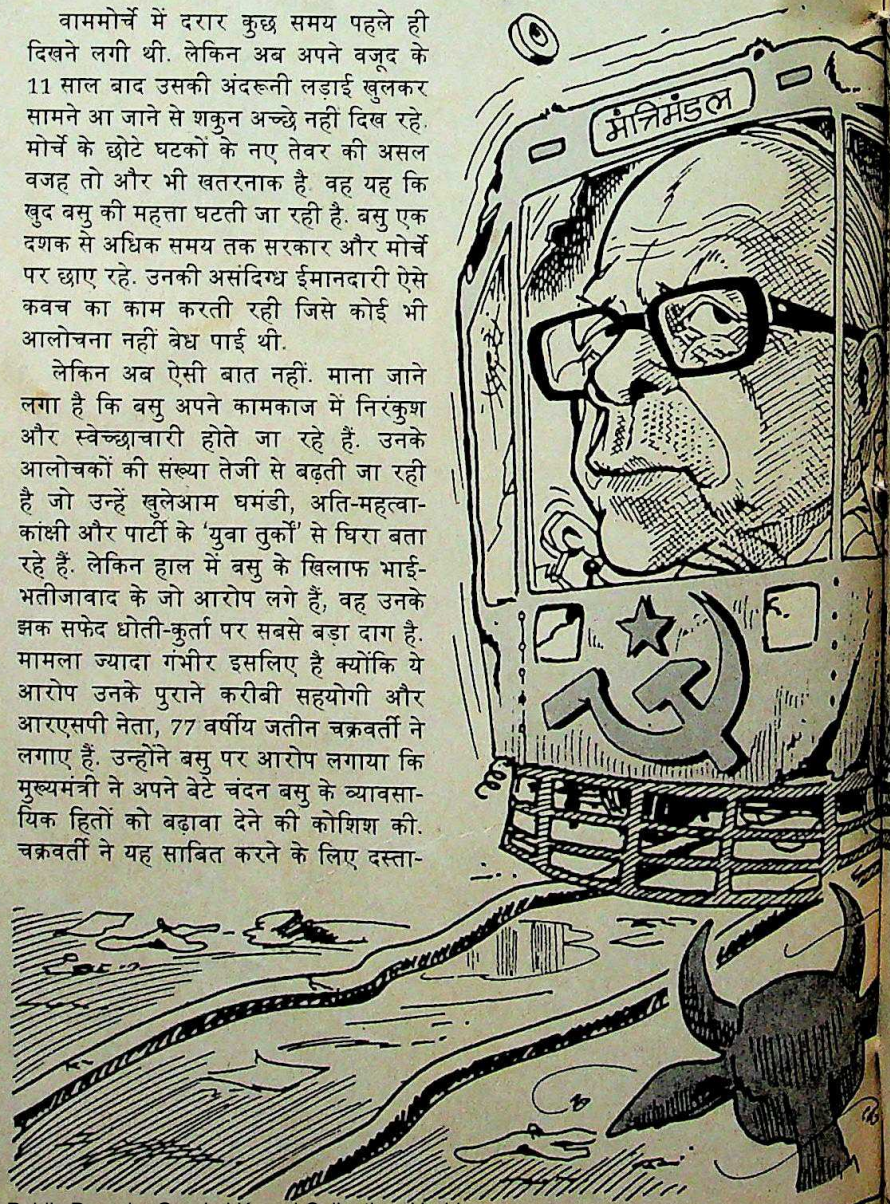

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी धुंधलाई कि चक्रवर्ती के फोन टेप किए जा रहे हैं. चक्रवर्ती के सचिव एस.एम. मुर्शीद ने सतर्कता विभाग को यह जांच करने के आदेश दिए थे कि उनके मंत्री के फोन किसने टेप किए हैं. पर इसके तुरंत बाद मुर्शीद का तबादला राज्य सचिवालय के बाहर कम महत्वपूर्ण पद पर कर दिया गया.

इस विवाद का फौरी असर यह हुआ कि वाममोर्चा के भीतर सभी लोगों के तेवर गरमा गए हैं. हाल की आलोचना से क्षुब्ध बसु ने वाममोर्चा अध्यक्ष सरोज मुखर्जी तक को आड़े हाथों लिया. विवाद पैदा होने के बाद हुई मोर्चे की पहली बैठक में बसु ने मुखर्जी से बहुत चिड़चिड़ेपन से कहा, "आप किस तरह के अध्यक्ष हैं? कोई आपकी बात ही नहीं सुनता." इस पर आरएसपी के प्रतिनिधि निखिल दास बोल उठे, "हम आप से नहीं डरते."

पिछले कुछ महीनों से मोर्चे के छोटे घटक, खासकर आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक महसूस करने लगे थे कि माकपा उन्हें किनारे लगाती जा रही है. वर्षों से माकपा जो ताकत बढ़ाती आई है उसका मुख्य तौर पर नुकसान आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक को उठाना पड़ा है. इंका पर कोई आंच नहीं आई. मतदाताओं में उसका करीब 42 फीसदी समर्थन बरकरार रहा है.

अभी तक मोर्चे के छोटे साझीदारों ने खुली आलोचना नहीं की थी क्योंकि मोर्चे से निकलने का मतलब चुनावी खुदकशी करना होता. इसलिए व्यावहारिक रणनीति यह बनती थी कि बसु की ही जड़ें खोदी जाएं. वे जानते हैं कि इस तरह की रणनीति से सिर्फ प्रचार ही नहीं मिलेगा बल्कि माकपा पर उनके प्रति और अधिक उदार होने के लिए दबाव भी पड़ेगा.

कार्टून: अजीत नैनन

छोटे साझीदारों में खुद को किनारे लगा दिए जाने की भावना 1987 के विधानसभा चुनावों के बाद पैदा हुई जब वाणिज्य और उद्योग, उच्च शिक्षा और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनसे ले लिए गए. लेकिन असली संकट इस साल फरवरी में पंचायत चुनावों के वक्त पैदा हुआ जब बसु ने खुलेआम उन पर पंचायत सीट वितरण फार्मूला के उल्लंघन का आरोप लगाया. उन्होंने मतदाताओं से सभी विवादास्पद सीटों पर आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवारों को हटाने की अपील भी की. फारवर्ड ब्लॉक के एक नेता कहते हैं, "हम अवाक रह गए. ज्योति बसु इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं?"

मगर आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि माकपा के बिमान बोस, बुद्धदेव भट्टाचार्य और अनिल विश्वास जैसे 'युवा तुर्क' नेता बसु को प्रभावित कर रहे हैं. आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक को प्रोत्साहन इसलिए भी मिला कि उन्होंने पंचायत चुनावों में पहले से ज्यादा सीटें जीतीं. माकपा के दिग्गज और केंद्रीय समिति के सदस्य बिमान बोस तर्क देते हैं, "हमारे ज्यादा शक्ति हासिल करने का मतलब है कि हम सक्रिय पार्टी हैं. मोर्चे के दूसरे साझीदारों को अपनी शक्ति बढ़ाने से किसी ने नहीं रोका है."

छोटे साझीदारों के लिए परेशानी की बात तो यह है कि माकपा उन्हें जड़ से खत्म करने की जबरदस्त कोशिश कर रही है. फारवर्ड ब्लॉक के एक नेता खेद जताते हैं, "1978 में हुए पहले पंचायत चुनाव में कूचबिहार जिले में हमें बहुमत मिला था. लेकिन 1983 में हुए पंचायत चुनाव में माकपा ने हमें अल्पमत में ला दिया." मोर्चे के सभी छोटे घटक महसूस करते हैं कि कम-से-कम आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक जैसे प्रमुख घटकों को जिला परिषद की अध्यक्षता बांटने के लिए कोई प्रणाली तय होनी चाहिए.

इन घटकों को इस बात से भी नाराजगी है कि गोरखालैंड समस्या के समाधान की बातचीत में उन्हें शामिल नहीं किया गया. आरएसपी के एक नेता ने शिकायत की, "हमें तो अंधेरे में रखा गया जबकि किसी व्यक्ति ने एक दैनिक को पर्वतीय विकास परिषद की प्रतिलिपि पहुंचा दी. लेकिन माकपा नेतृत्व ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की."

फारवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने माकपा की इस बात के लिए भी आलोचना की है कि वह कम दर पर राशन देकर पुलिस को पटा रही है लेकिन वही सुविधा भूमिहीन मजदूरों को नहीं दे रही. माकपा द्वारा लोगों को खुश करने वाले कार्यक्रम शुरू करने पर भाकपा भी आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक के साथ उसकी आलोचना करने लगी है. माकपा ने राज्य में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी है. भाकपा के एक नेता ने कहा, "अप्रत्यक्ष रूप से माकपा ने अभिजात्य वर्ग की ही मदद की है."

राज्य एटक अध्यक्ष और बुजुर्ग मजदूर नेता भवानी राय चौधरी बेलाग कहते हैं, "11 वर्षों में हम आम लोगों, किसानों, और मजदूरों की इच्छाओं को पूरा करने में विफल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहे हैं. हम सामाजिक परिवर्तन नहीं ला पाए.'' पर भाकपा को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर है कि माकपा अपनी शक्ति बढाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है.

भाकपा के बंगला मुखपत्र 'साप्ताहिक कालांतर' के 24 सितंबर के अंक में कहा गया है, ''आजकल नौकरशाही मोर्चे की सबसे बड़ी पार्टी की बेहद तरफदारी कर रही है. इतनी भारी ताकत पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता फूले नहीं समाते. वे मोर्चे के दूसरे साझीदारों को न सिर्फ उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं बल्कि चाहते हैं कि वे कमजोर बने रहें.'' भाकपा सांसद नारायण चौबे ने हाल ही में माकपा पर आरोप लगाया था कि वह भाकपा को उसके प्रभाव वाले खड़गपुर कस्बे और मिदनापुर जिले के दूसरे क्षेत्रों से खत्म करने के लिए 'वैगन चोरों और समाजविरोधी तत्वों' की मदद ले रही है. दरअसल, नारायण चौबे के पुत्र गौतम चौबे पर जानलेवा हमले के कारण उनकी पत्नी गौरी चौबे भाकपा से इस्तीफा देकर इंका में शामिल हो गई थीं. गौरी चौबे कहती हैं, ''मैंने अपने पति को भी भाकपा से इस्तीफा देने के लिए कहा क्योंकि ऐसी पार्टी में बने रहने की क्या तुक है जिसकी साझीदार पार्टियां ही आपको खत्म करने पर तुल गई हों.''

मोर्चे के घटकों के बीच होने वाली खूनी झड़पों से पता चलता है कि उसमें कितनी दरारें हैं. पुलिस इन झड़पों के आंकड़े देने से इनकार करती है. पर उसका मानना है कि पिछले दो वर्षों में माकपा, आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक के समर्थकों के बीच हुई झड़पों में कई लोग मारे गए. ज्यादातर झड़पें पश्चिमी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर जिलों में हुईं जहां आरएसपी, फारवर्ड ब्लॉक और भाकपा का आधार है.

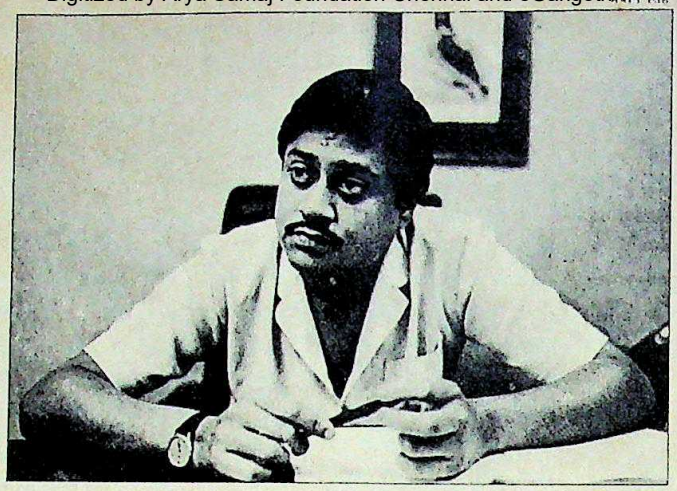

भवान सिंह

चंदन बसुः आरोपों की आंच

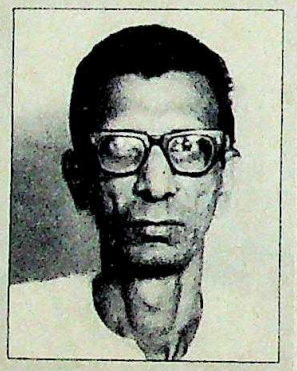

"लगता है माकपा हमें स्टालिनवादी तरीके से खत्म करने पर आमादा है"

देबव्रत बंद्योपाध्याय
सिंचाईमंत्री और आरएसपी नेता

"घटकों का यही रवैया रहा तो मोर्चे में उनके बने रहने का क्या औचित्य है"

सरोज मुखर्जी
वाममोर्चा अध्यक्ष और राज्य माकपा सचिव

छोटे घटकों ने यह आरोप भी लगाया है कि माकपा उनकी शाखाओं को प्रशासन की मदद से खत्म कर रही है. राज्य के जेलमंत्री और आरएसपी नेता विश्वनाथ चौधरी ने माकपा पर आरएसपी जेल कर्मचारी संघ को खत्म करने की गरज से ही एक समानांतर कर्मचारी संघ बनाने का आरोप लगाया. आरएसपी नेता और राज्य के सिंचाईमंत्री देबव्रत बंद्योपाध्याय कहते हैं, ''माकपा की निरंकुशता मोर्चे को बरबाद कर रही है.''

मोर्चे के छोटे साझीदारों में बेचैनी का असली सबब तो राज्य सरकार की वह बड़ी सफलता है जो उसने पिछले 11 साल में हासिल की है. उसने 'ऑपरेशन बर्गा' और पंचायती राज वाले दो कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है. इसकी वजह से जिलों में शक्ति का आधार कारगर तौर पर स्थानीय माकपा कार्यकर्ताओं के नियंत्रण में आ गया है. राज्य में सभी जिला परिषदें चूंकि माकपा नेताओं के हाथ में हैं, लिहाजा वे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं.

मोटे अनुमान के मुताबिक पंचायती राज के कारण ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए हर साल 1,000 करोड़ रुपए आते हैं. कृषि, सिंचाई, बुनियादी विकास और जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग से संबंधित सभी विकास परियोजनाएं जिला परिषद प्रमुखों द्वारा नियंत्रित होती हैं. एनआरईपी, आईआरडीपी जैसे केंद्रीय कार्यक्रम भी इन्हीं लोगों के हाथ में हैं. राज्य में जिला परिषदों के सभी अध्यक्ष चूंकि माकपा नेता हैं, लिहाजा इतनी विशाल धनराशि के कर्ताधर्ता भी वही हैं. इससे छोटे घटकों में असंतोष फैला है.

अब सवाल यह है कि क्या छोटे साझीदार इस दबाव को बनाए रखकर माकपा नेतृत्व से कुछ रियायत हासिल कर सकते हैं या फिर मौजूदा लड़ाई जारी रहेगी. वाममोर्चा एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मोर्चा उस समय तक ही बरकरार रहेगा जब तक उसके घटकों के वरिष्ठ नेता जिंदा हैं और उनमें दमखम है.

इस बात के मद्देनजर कि माकपा के सरोज मुखर्जी, विनयकृष्ण चौधरी और ज्योति बसु आरएसपी के माखन पाल; भाकपा के विश्वनाथ मुखर्जी और फारवर्ड ब्लॉक के चित्त बसु सरीखे दिग्गजों की उम्र 75 को पार कर गई है, वाममोर्चा के पास इतना वक्त नहीं बचा है कि वह अपना घर व्यवस्थित कर सके.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

क्या समझे !

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai

मेरी पत्नी ने कहा।
"लेकिन..."
"हम कौन सा हर दूसरे दिन नया घर बनाते हैं।" उसने मेरी बात काटते हुए कहा।
"पर..." मैंने फिर कुछ कहना चाहा।
"मैं कुछ सुनना नहीं चाहती" वह बोली,
"तुम सुपर जेके सिमेंट ही लाओगे,
समझे?" इतना कह कर वह कमरे से बाहर चली गयी।
"समझ गया" मैं बोला।
अपनी बात उसके मुँह से कहलवाना मैं खूब जानता हूँ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

SUPER JK CEMENT

सुपर जे के सिमेंट

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परिवार नियोजन कार्यक्रम

फरेब का पर्दाफाश

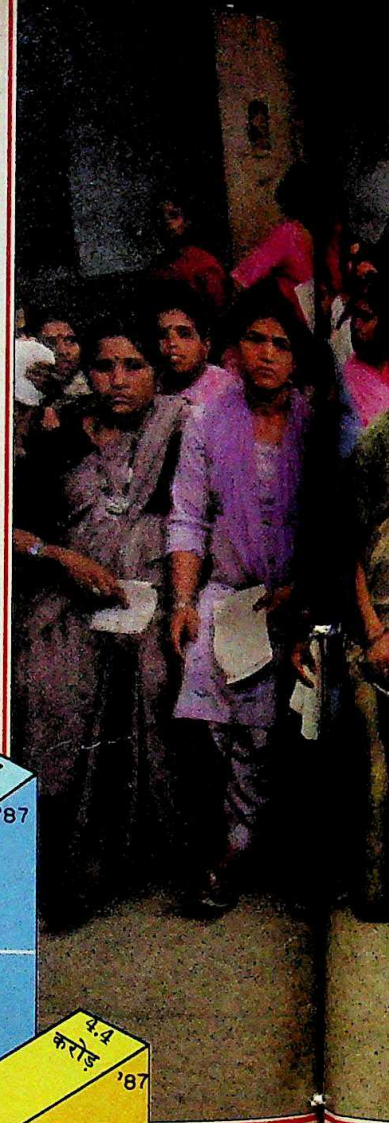

चार्ट: बी.के. शर्मा

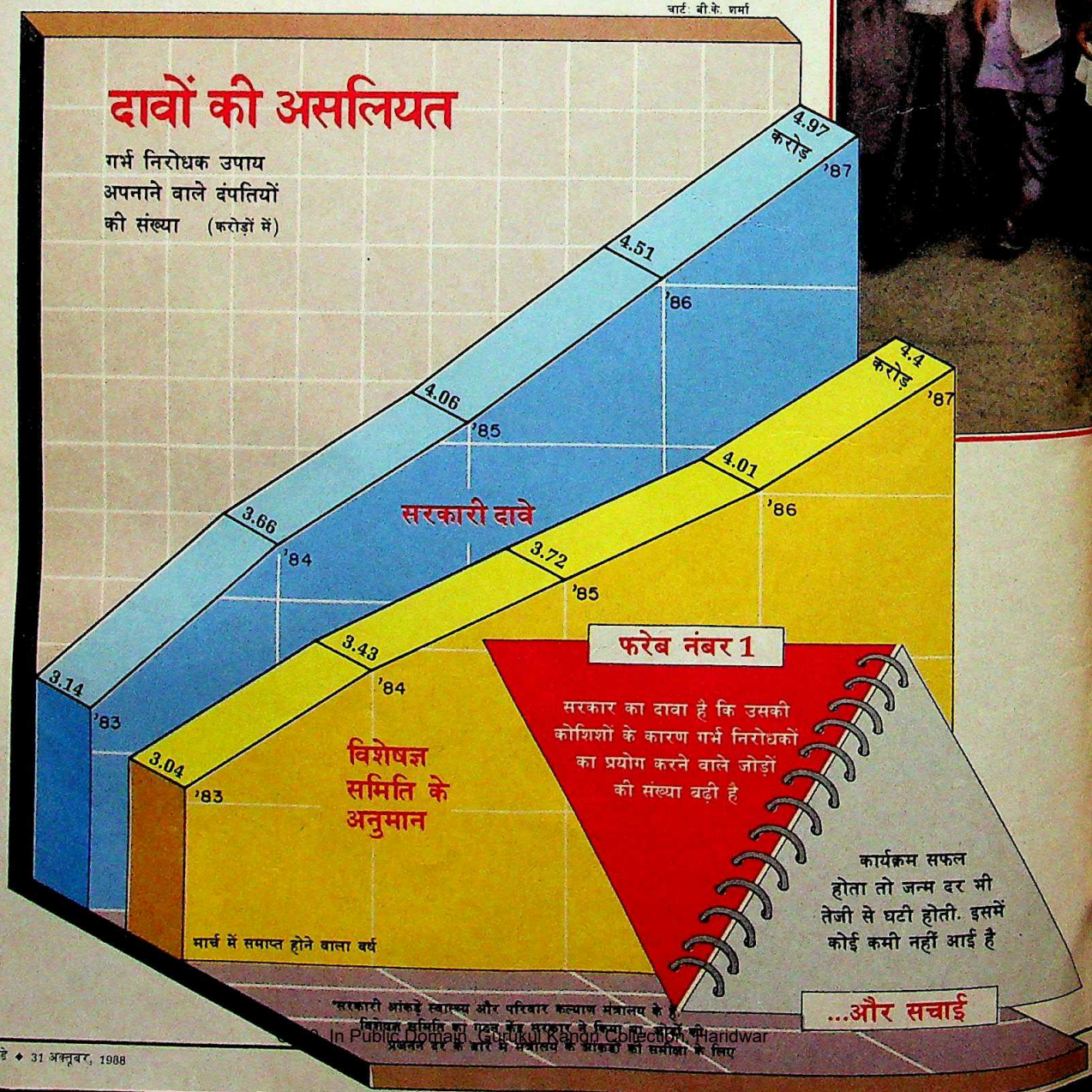

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj

रघु राय

दिल्ली के एक अस्पताल में जांच करवाने आई गर्भवती महिलाएं: बच्चों की बाढ़

बंबई की घनी आबादी वाले उपनगर चेंबूर में एक अंधेरे हॉल में सोने की चमक वाली एक घड़ी निरंतर टिक-टिक करती रहती है. लेकिन इसकी सुइयां समय को नहीं मापतीं. यह 1.2 सेकेंड में एक बार टिक करती है. यह माप है भारतीय आबादी में निरंतर होती वृद्धि का. यानी हर 1.2 सेकेंड पर एक नया मेहमान जन्म ले लेता है इस देश में—एक मिनट में 50 और एक घंटे में 3000.

सरकारी अनुदान प्राप्त अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (अंजविसं) में लगाई गई इस घड़ी ने इस वर्ष 15 अगस्त को एक नया कीर्तिमान बना डाला—80 करोड़ बार धड़कने का. देश की आबादी सालाना 2.13 फीसदी की दर से लगातार बढ़ रही है. योजना आयोग के सदस्य पी.एन. श्रीवास्तव के शब्दों में, "भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है."

यह रफ्तार 1977 से स्थिर है. इसमें गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखते. और यह स्थिति तब है जब सरकार ने पिछले दशक में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कुल 3000 करोड़ रुपए खर्च किए. और तो और, सरकार का दावा है कि उसकी कोशिशों के कारण गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करने वाले जोड़ों की संख्या 1980 के 2.64 करोड़ से दूनी होकर पिछले साल 5.4 करोड़ हो गई.

लेकिन सरकारी दावे की पोल महापंजियक के इस तथ्य से खुल जाती है कि 1977 के बाद से हर साल प्रत्येक एक हजार की आबादी में 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं. जनसंख्याविदों के शब्दों में इसे अपरिपक्व जन्म दर कहा जाता है. लेकिन परिवार नियोजन के सरकारी कार्यक्रम की सफलता का सबसे अहम पैमाना यही है.

अगर कार्यक्रम सफल हो रहा होता तो जन्म दर में कमी होनी चाहिए थी. लेकिन पिछले एक दशक में इसमें रत्ती भर भी गिरावट नहीं आई है. जनसंख्या विशेषज्ञ और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्के आलोचक आशीष बोस कहते हैं, "सरकारी दावा सिर्फ खर्च में बढ़ोतरी की सफलता ही दर्शाती है. सरकार के हिसाब से तो हर चीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए. दुर्भाग्य से जनसंख्या भी बढ़ती ही जा रही है." और यह तो सर्वमान्य तथ्य ही है कि जनसंख्या में तेज वृद्धि ही देश के तीव्र विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है. देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को बड़ा करने पर ही देश के 16,000 रुपए खर्च होते हैं.

भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था. कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया. तब से इसने बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के सारे तरीके आजमा लिए हैं. लेकिन जैसा कि नीति अनुसंधान केंद्र के पई पाणंदीकर कहते हैं, "लगता है कि भारत में यह कार्यक्रम अपनी 'सेक्स अपील' खो बैठा है."

1984 में जब राजीव गांधी ने बागडोर थामी तो नए तरह के कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. नए तरह से विचार हुए, नए नारे आए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बच्चों के जन्म में अंतर बढ़ाने और जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बातें की जाने लगीं. विशेषज्ञों ने ऐसे कार्यक्रमों पर जोर देने की बात की जिनके तहत अभिभावकों को अपनी लड़कियों की शादी देर से करने पर राजी किया जाए. कहा गया कि इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने, औरतों में साक्षरता बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र करने में मदद मिलेगी. लेकिन चार साल बीत रहे हैं, कोई क्रांति होती नजर नहीं आती. केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय अपने तौरतरीकों में कोई फेरबदल करता नहीं दिख रहा. इन कार्यक्रमों के बारे में फरेबी दावे करने का उसका रवैया जारी है. और इन झांसों का नतीजा यह है कि लोग निरंतर खतरनाक रूप से टिक-टिक कर रहे 'आबादी बम' की ओर से बेखबर होते जा रहे हैं. प्रस्तुत हैं इन फरेबों के कुछ नमूने.

फरेब नं. 1

"पिछले साल परिवार नियोजन के उपायों को 2.05 करोड़ नए जोड़ों ने अपनाया जो अब तक का रिकार्ड है. यह कड़ी मेहनत, सभी संसाधनों के भरपूर इस्तेमाल और राज्यों के नए अभिक्रम से संभव हो पाया है. इसके लिए राज्य सरकारें बधाई की पात्र हैं."

—केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण परिषद का पहला सम्मेलन, फरवरी 1988

सचाई: कहा जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को 'टार्गेटाइटिस' (लक्ष्य रोग) लग गया है. इसका लक्षण है लगातार आंकड़ों के पीछे भागना और सफलता के दिवास्वप्न देखना.

लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर वेहेंदो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी पिछले दिनों 80 वर्षीय छोटेलाल और उसके 40 वर्षीय बेटे लक्ष्मण की नसबंदी की गई. इन दोनों ने नसबंदी के एवज में सरकार से मिलने वाले 180 रुपयों की खातिर ही दोबारा ऑपरेशन कराया. पुणे से 50 किमी दूर केंदुर स्वास्थ्य केंद्र में दूसरे तरह का ही फरेब रचा जा रहा था. पिछले महीने यहां 35 वर्षीया मंदाकी रामचंद्र का वंध्याकरण किया गया. उसके चार बेटियां और एक बेटा है.

राष्ट्रीय आंकड़ों में ये तीनों मामले भी गर्भ निरोधक उपाय अपनाने वाले 'नए जोड़े' या 'सुरक्षित जोड़े' मान लिए जाएंगे. रामचंद्र दंपती की तरह ही 'सुरक्षित' बताए जाने वाले दो-तिहाई जोड़ों के पति-पत्नियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और उन्हें चार या अधिक बच्चे हो चुके हैं. 'अंजविस' के प्रमुख प्रो. के. श्रीनिवासन कहते हैं, "यह तो चिड़िया के दाना चुग जाने के बाद जाल फेंकने वाली बात हुई." अहम तथ्य तो यह है कि 15 से 29 आयु वर्ग वाले जोड़ों में से, जिन्हें सबसे प्रजननशील माना जाता है, केवल 16 फीसदी जोड़ों ने ही गर्भ निरोधक उपायों को अपनाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि गर्भ धारण से सुरक्षित जोड़ों का प्रतिशत 1980 के 22.8 से बढ़कर 39.9 पर आ गया है. यानी आठ साल में 17 फीसदी की बढ़ोतरी. इस हिसाब से तो अभी तक जनसंख्या वृद्धि दर प्रति हजार 28 तक आ जानी चाहिए थी. लेकिन 1977 से यह 33 पर ही अटकी है.

बच्चे पैदा करने में अक्षम जोड़ों की नसबंदी करना और उपलब्धियों के गलत-सलत आंकड़े देना राज्यों में व्यापक तौर पर चल रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य गुप्तचर रिपोर्टों में यह बार-बार कहा गया है कि अधिकाश राज्य गर्भ निरोधक उपाय अपनाने वाले नए जोड़ों की जो सूची देते हैं उनमें से 14 से 20 फीसदी नाम तो

रघु राय

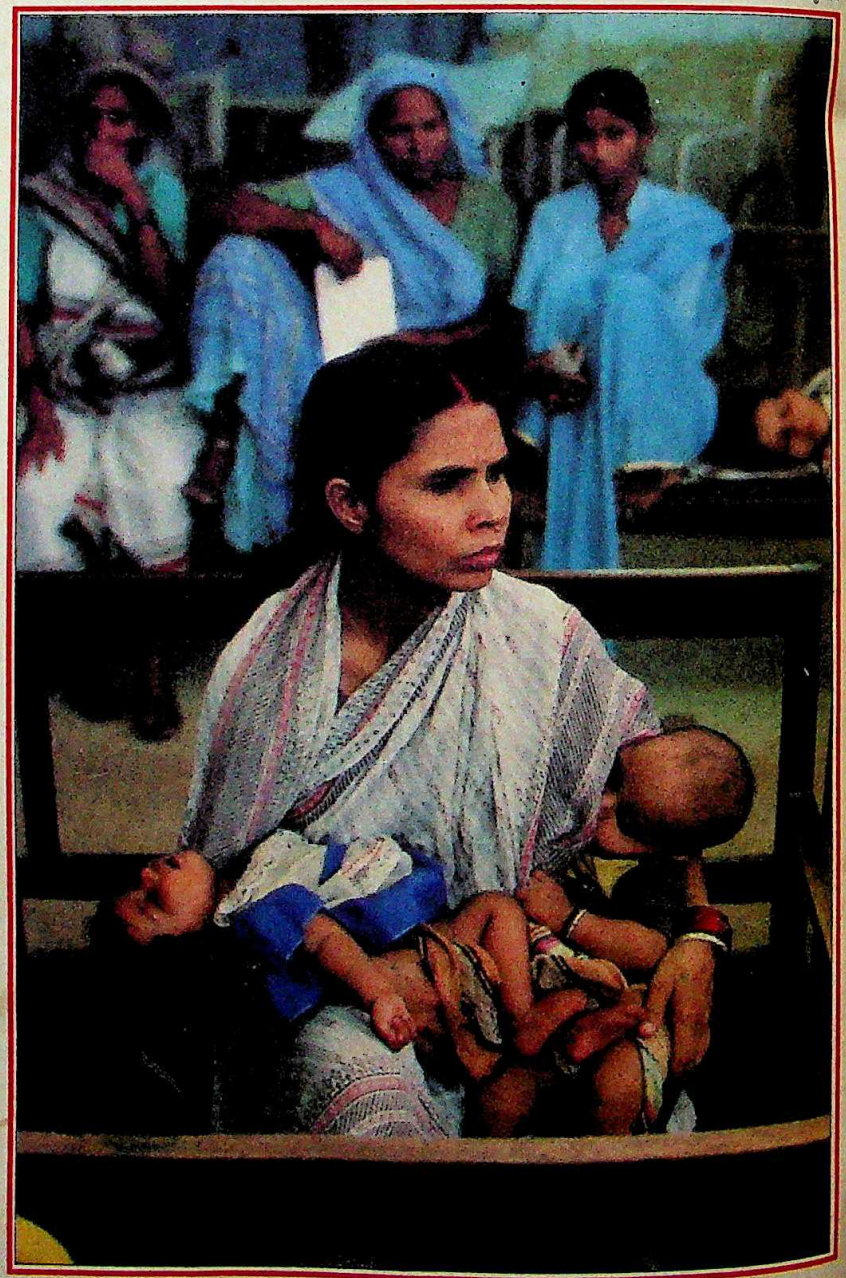

मां और दो बच्चे: जन्म के समय में अंतर का कार्यक्रम विफल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फरेब नंबर 2

स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि बच्चों के जन्म में फासला बढ़ाने के उपायों को लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम सफल है

लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ दल ने पाया कि आंकड़े गलत थे इसलिए उसने इनमें कटौती की

...और सचाई

फरेब नं. 2 *"बच्चों के जन्म के बीच फासला बढ़ाने के उपायों को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने हाल में एक नई नीति शुरू की है. कॉपर-टी लगवाने वाली महिलाओं की संख्या इधर तेजी से बढ़ी है और गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग तीन गुना बढ़ गया है. साथ ही कंडोम का इस्तेमाल करने वाले जोड़ों की संख्या भी बढ़ रही है."*

—भारत सरकार, अगस्त 1984 में मेक्सिको में हुए अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन में

सचाई: स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगा कि नसबंदी तो अंतिम व स्थायी तरीका है और लोग तभी नसबंदी कराना चाहते हैं जब उन्हें मनचाही संख्या या सेक्स की संतानें हो चुकी होती हैं. इसकी जगह अगर लोगों को पहले बच्चे में जल्दी न करने और उसके बाद के बच्चों के जन्म के बीच दो या तीन वर्ष का फासला रखने के लिए राजी किया जा सके तो परिवार के आकार को काफी छोटा रखा जा सकता है. इसके लिए देश भर के ग्रामीण इलाकों में भी कंडोम, खाने की गोलियां और कॉपर-टी वगैरह बड़ी संख्या में भेजे गए.

लेकिन यह कार्यक्रम भी सही रास्ते और रफ्तार पर नहीं आ पाया है. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ता पी.एल. शर्मा (छद्म नाम) कहते हैं, "बच्चों के जन्म के बीच फासला बढ़ाने के लिए दंपतियों को समझाने-बुझाने में न तो किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दिलचस्पी है और न ही उसके पास इसके लिए समय है. हमें तो हर संमय रजिस्टर पर अपना तय कोटा पूरा करने की चिंता लगी रहती है. कागजी काम इस सफाई से किया जाता है कि आंकड़ों में गड़बड़ी की गई है यह कोई पकड़ ही नहीं सकता."

हर जगह यही हालत है. सारी बातें जांची नहीं जा सकतीं. इसलिए सरकारी झांसेबाजी चलती जा रही है. मसलन कंडोम के इस्तेमाल से सुरक्षित माने जाने वाले जोड़ों की संख्या उन जोड़ों की संख्या मान ली जाती है जिन्हें कंडोम बांट दिया गया है. कई अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कॉपर-टी लगवाने वाली महिलाएं शायद ही उसे छह महीने से अधिक तक लगाए रहती हैं. सुरक्षित जोड़ों के अध्ययन के लिए बनी सरकारी कमेटी भी मानती है कि "कॉपर-टी लगाने और कंडोम तथा गर्भ निरोधक गोलियों को बांटने के बारे में दावे बढ़ा-चढ़ाकर किए गए लगते हैं."

लेकिन समस्या सिर्फ आंकड़ों में हेराफेरी की ही नहीं है. पूरा स्वास्थ्य महकमा अभी भी नसबंदी या वंध्याकरण के लक्ष्यों के लिए ही सक्रिय है. कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियों और कॉपर-टी वगैरह के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन, निगरानी और इन चीजों की नियमित आपूर्ति की जरूरत होती है.

पुरानी सामाजिक मान्यताएं भी इस अभियान के मार्ग में कुछ हद तक बाधक हैं. जहां मासिक धर्म के दौरान छुआछूत बरता जाता है वहां कॉपर-टी लगवाने से अनियमित रक्तस्राव को असुविधाजनक ही तो माना जाएगा. अपने यहां कॉपर-टी लगवाने वाली औरतों की औसत उम्र साढ़े सत्ताइस वर्ष है. तब तक उन्हें चार या अधिक बच्चे हो चुके होते हैं. गर्भ निरोधक गोलियों पर तो सिर्फ लोगों को ही नहीं, डॉक्टरों को भी भरोसा नहीं है.

बच्चों के जन्म के बीच फासला बढ़ाने के कार्यक्रम की असफलता का एक कारण गर्भपात वगैरह की सुविधा का न होना भी है. भारत में प्रति वर्ष सिर्फ पांच लाख गर्भपात ही कराए जाते हैं. जयपुर के भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. रामेश्वर शर्मा कहते हैं, "यह शायद मजाक लगे लेकिन सच यह है कि गर्भ निरोध का सर्वोत्तम तरीका स्तनपान कराना ही है. अभी तक यही सबसे कारगर रहा है. इसका श्रेय सरकारी प्रयासों को कतई नहीं जाता." लेकिन स्तनपान कराना चाहे कितना भी अच्छा तरीका क्यों न हो, इससे गर्भ धारण सिर्फ साल भर तक ही टल सकता है.

फरेब नं. 3 *"बेटी हो या बेटे, बच्चे दो ही अच्छे."*

—परिवार नियोजन का नारा

सचाई: जिस देश में बेटा पैदा करना धर्म माना जाता हो उस देश में यह नारा बचकानेपन के अलावा क्या हो सकता है. एक विशेषज्ञ का कहना है कि लोगों ने अपना न्यूनतम कार्यक्रम—दो बेटे पैदा करना—खुद ही तय कर लिया है. महाराष्ट्र के पिंपले जगताप गांव के दत्ता राज, जो तीन लड़कियों और एक बेटे के पिता हैं, कहते हैं, "मुझे दो बेटे चाहिए वरना कौन मेरी चिता में आग लगाएगा, कौन मेरा वंश चलाएगा, कौन खेती के काम में मदद करेगा और कौन बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा?"

देश भर में सभी जगह लगभग इसी तरह की बातें सुनी जा सकती हैं. राजस्थान के फागी के चांदमल जैन कहते हैं, "बेटे हमारी आंखों की तरह हैं. उनके बिना हम कुछ नहीं देख सकते. और अच्छी तरह देखने के लिए

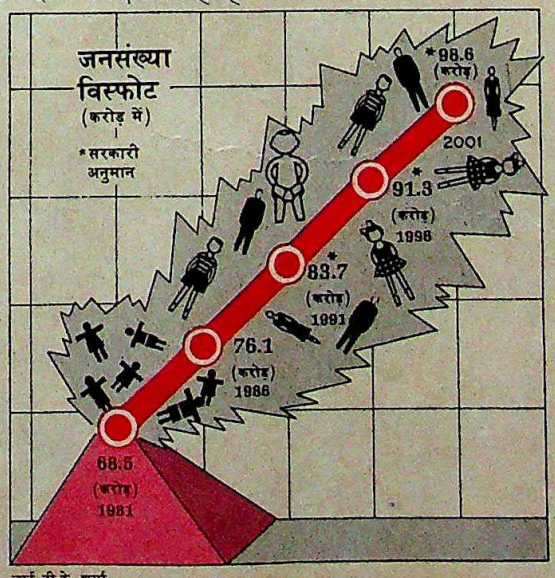

चार्ट बी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दो आंखों की जरूरत होती है.'' उत्तर प्रदेश के गांवों में लोग दो बेटों को सहारे की दो लाठियां मानते हैं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि औरतें भी बेटों को उतना ही महत्व देती हैं.

इससे भी बड़ी बात यह है कि छोटे परिवार का नारा अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है क्योंकि अब तक पूरा कार्यक्रम सिर्फ जनसांख्यिकीय लक्ष्य के लिए ही चलता रहा है. लोगों की संतान की जरूरतों के प्रति सरकार आंखें ही मूंदे हुए है. 30 वर्ष की उम्र में चार बच्चों के बाप हो चुके राजस्थान के रामस्वरूप शर्मा कहते हैं, ''मुझे कम-से-कम पांच बच्चे चाहिए. एक बकरी चराने के लिए, एक गायों के लिए, एक भेड़ के लिए, एक खेती के काम में मेरी मदद के लिए और एक घर के काम में पत्नी की मदद के लिए.'' शर्मा की बातों से साफ है कि अधिकांश भारतीय दो से अधिक बच्चे किन कारणों से चाहते हैं. बच्चे आर्थिक जरूरतों में शुमार हैं और उन्हें बुढ़ापे का सहारा माना जाता है. बंबई में परिवार नियोजन संघ की अनुसंधान निदेशक शिरीन जीजीभॉय कहती हैं, ''लोग खरगोश की तरह बच्चे पैदा नहीं करते. उनका अपना तर्क होता है. उनके लिए बेटों का मतलब बुढ़ापे की पेंशन, अधिक बच्चों का मतलब कमाने वाले अधिक हाथ हैं. क्या सरकार कोई विकल्प दे रही है?'' अभी तक तो सरकार ने कोई विकल्प नहीं दिया है.

33-34 है. बाल मृत्यु दर भी इन राज्यों में सबसे ऊंची है.

इन राज्यों के पिछड़ने से अन्य राज्यों की उपलब्धियों पर भी पानी फिर जाता है. केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम के अगुआ हैं. केरल की सफलता का कारण वहां की औरतों में साक्षरता का अधिक होना, अधिक उम्र में शादी करना और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध होना है.

इन तत्वों पर ध्यान देने के बजाय ये 'बिमारू' राज्य सिर्फ परिवार नियोजन के लक्ष्य हासिल करने की धुन में लगे रहते हैं. इस पागलपन की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर राज्य के लिए लक्ष्य तय करने के साथ ही होती है.

इस लक्ष्य को पूरा करने की भारी-भरकम सरकारी 'कसरत' का असर कई राज्यों में उलटा ही दिखने लगा है. लखनऊ के निकट के मोहनलालगंज के एक डॉक्टर बताते हैं, ''हमारा सारा जोर इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने पर केंद्रित रहता है. स्वास्थ्य संबंधी दूसरे काम एकदम उपेक्षित रहते हैं. अगर हम लक्ष्य हासिल नहीं करते तो हमारी वेतन वृद्धि रुक जाती है या हमें किसी 'खराब' स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है.'' दूसरे डॉक्टर कहते हैं, ''किसी भी तरह के जोड़ों को इस कार्यक्रम में शामिल करके लक्ष्य हासिल किया जाता है.''

परिवार नियोजन शिविर लगाकर भी लक्ष्य पूरे किए जाते हैं. ऐसे

फरेब नं. 4

''परिवार नियोजन कार्यक्रमों में हरदम लक्ष्य से अधिक काम करने के लिए उत्तर प्रदेश निरंतर पुरस्कार लेता रहा है. हमने पहले की तुलना में अब ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं.''

—मोहिंदर सिंह, राज्य स्वास्थ्य अधिकारी

सचाई: यह नौटंकी दिल्ली में राज्यों के परिवार कल्याण विभागों की वार्षिक बैठक में हर बार खेली जाती है. यह बैठक विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाई जाती है. स्वास्थ्यमंत्रियों और सचिवों का मेला लगता है और परिवार नियोजन के लक्ष्य हासिल करने पर पुरस्कार बांटे जाते हैं. प्रथम पुरस्कार, 115 फीसदी सफलता के लिए उत्तर प्रदेश को! तालियां.... द्वितीय पुरस्कार, 95 फीसदी लक्ष्य हासिल करने पर राजस्थान को! फिर तालियां...

लेकिन यह बात कभी नहीं बताई जाती कि उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिलता है तो सिर्फ इसलिए कि उसके ग्रुप में राजस्थान और बिहार जैसे सुस्त राज्य हैं. दरअसल बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान परिवार नियोजन कार्यक्रम में देश में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं. इन राज्यों के पहले अक्षर को लेकर बोस ने इसे 'बिमारू' का विशेषण दिया है. इन राज्यों में पिछले छह वर्षों से जन्म दर प्रति हजार आबादी पर 38 से 39 के बीच रही है जबकि राष्ट्रीय औसत

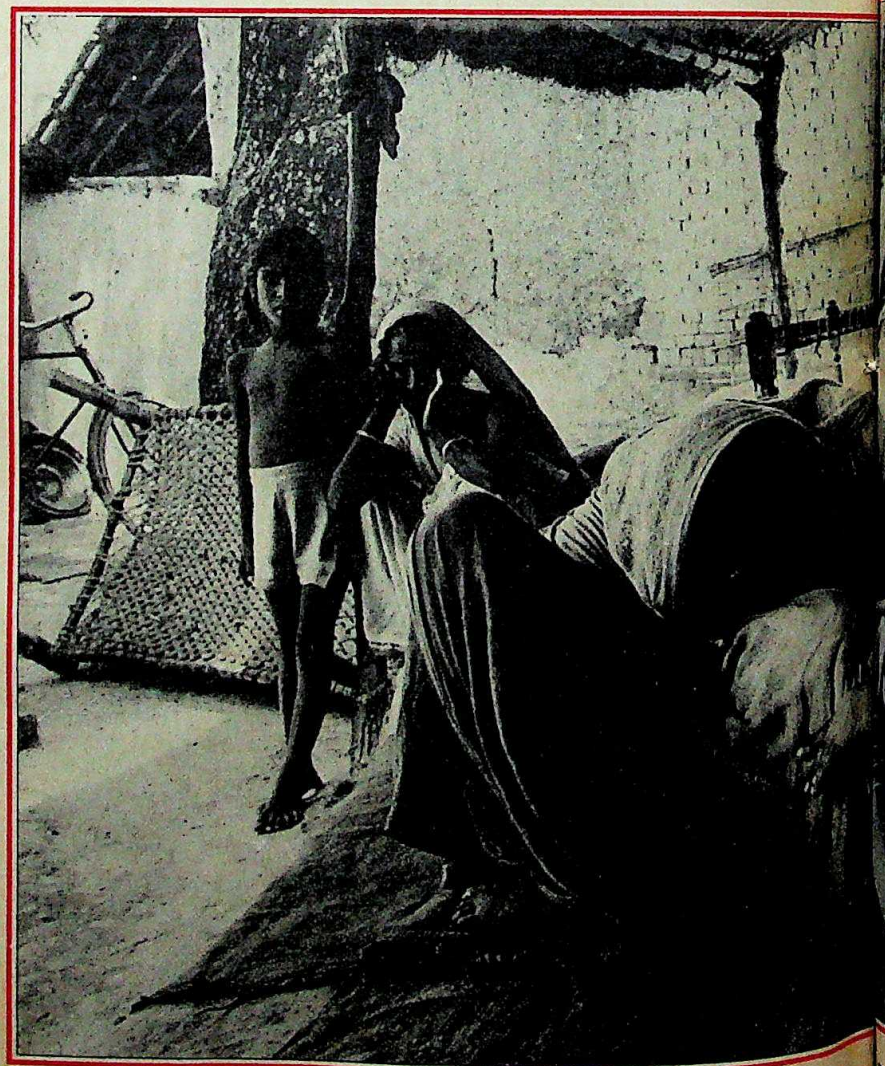

गर्भवती महिला की जांच करती दाई: गांवों में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिविर मानसून के बाद से लगने शुरू होते हैं और वित्त वर्ष खत्म होने के समय इनका जोर बढ़ जाता है. नए जोड़ों को मनाने के लिए हर तरीके का प्रयोग किया जाता है. मार्च आते-आते प्रोत्साहन के तौर पर मुफ्त कंबल, बाल्टी या ट्रांजिस्टर तक बंटना भी शुरू हो जाता है. नसबंदी कराने वाले नौजवान लोगों को जमीन का प्लॉट देने का वायदा (जो कभी पूरा नहीं होता) भी किया जाता है. उत्तर प्रदेश के मंडिला तालुके के राधेलाल और कल्याणी को नसबंदी कराने पर जमीन देने का वादा किया गया. दोनों के दो बच्चे थे. कल्याणी का वंध्याकरण तो पिछले साल हो गया पर जमीन के दर्शन नहीं हुए.

यह सब करके सभी केंद्र अपना कोटा पूरा कर तो लेते हैं लेकिन उनके कागजात में उन लोगों के नाम भी दर्ज रहते हैं जो या तो चार पांच बच्चे पैदा कर चुके होते हैं या जो संतान उत्पन्न ही नहीं कर सकते. जब लखनऊ के जनसंख्या अनुसंधान केंद्र ने नसबंदी कराने वालों के बारे में एक सर्वेक्षण कराया तो उसे रिकार्ड में दर्ज एक-तिहाई लोगों का अता-पता ही नहीं मिल पाया. केंद्र के निदेशक डॉ. भास्कर मिश्र कहते हैं, "स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मानकर काम करते हैं. जैसे डीडीटी छिड़का जाता है वैसे ही वे वहां गर्भ निरोधक 'छिड़कते' फिरते हैं. और इस सबका नतीजा यह है कि आंकड़ों के प्रभावशाली दिखने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभावी रोक नहीं लग पाती."

फरेब नंबर 3

उत्तर प्रदेश को पिछले वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम में लक्ष्य से अधिक काम करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला

लेकिन यह नहीं बताया जाता कि उसे बिहार और राजस्थान जैसे सुस्त राज्यों के ग्रुप में शामिल किया गया

...और सचाई

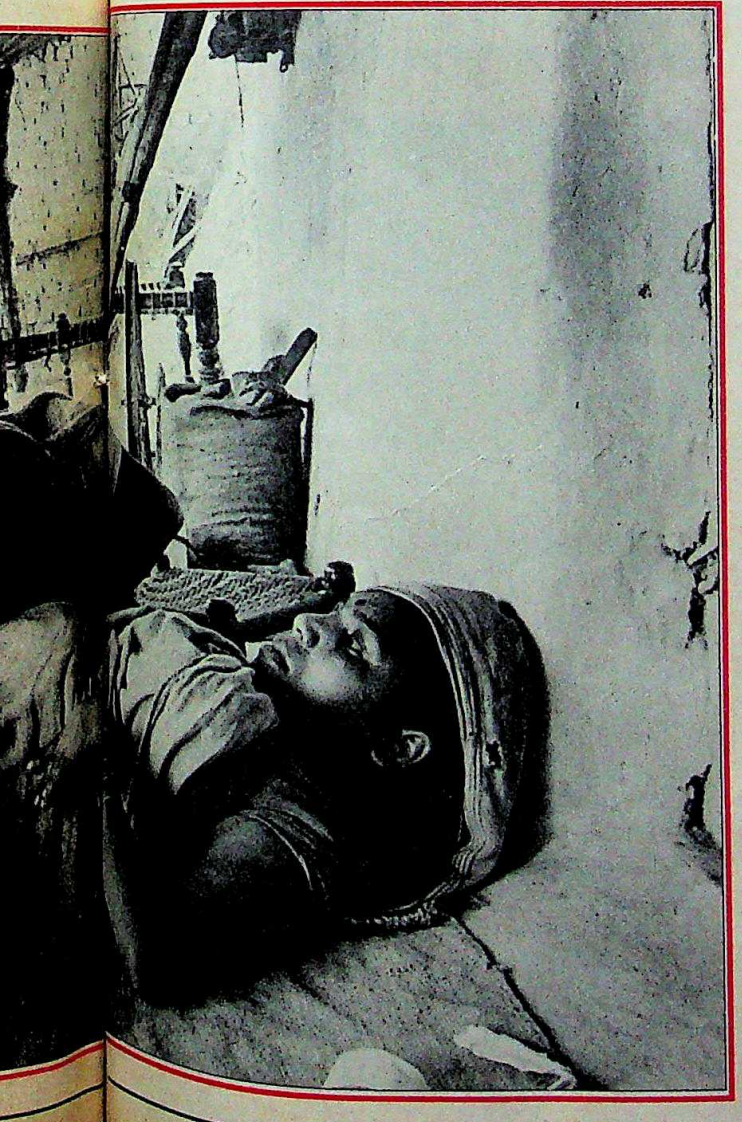

फरेब न. 5

"माताओं और बच्चों की देखभाल के कार्यक्रम का व्यापक विस्तार हुआ है. टीकाकरण वगैरह के प्रयास बच्चों और माताओं की मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से हो रहे हैं."

—परिवार कल्याण मंत्रालय की पुस्तिका, 1988

सचाई : लखनऊ से 50 किमी दूर सिसेंडी में रानी नामक महिला को भोर में चार बजे से हल्का दर्द शुरू हुआ. लेकिन उसने अपने पति के लिए परांठे बनाना जारी रखा. उसका पति आम दिनों की तरह ही काम करने खेतों में चला गया. जब रानी का दर्द बढ़ गया तो दाई माया देवी को बुलाया गया. वह अपने साथ महज चंद सीधे-सादे सामान लेकर आई— नाल काटने के लिए ब्लेड, बच्चे को साफ करने के लिए गरम पानी में भिगोने के लिए पुराना कपड़ा और कटी नाल पर मलने के लिए थोड़ी राख. थोड़ी देर बाद ही एक बच्ची ने जन्म लिया. प्रसव में कोई विशेष झंझट नहीं हुआ.

राज्यों की सरकारों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में 'भारी सुधार' के दावे के बावजूद आज भी गांवों में दस में से नौ बच्चे दाइयों की देखरेख में पैदा होते हैं. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा पांच राज्यों में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक प्रशिक्षित सरकारी दाइयां शायद ही किसी गर्भवती महिला की देखभाल करती हैं, और सिर्फ दस फीसदी मामलों में ही वे बच्चे के जन्म के समय मौजूद होती हैं. जच्चा-बच्चा की मौत का बहुत बड़ा कारण टेटनस और रक्ताल्पता है लेकिन सिर्फ 30 फीसदी स्त्रियों को ही टेटनस की सुई और मुश्किल से 20 फीसदी को ही रक्ताल्पता समाप्त करने वाली गोलियां मिल पाती हैं. अधिकांश बच्चों को रोग अवरोधी तिहरे टीके भी नहीं लग पाते.

परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता-असफलता का श्रेय बहुत कुछ प्रशिक्षित दाइयों पर है. लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है. प्रशिक्षण भी कम मिला होता है और इस पूरे कार्यक्रम में वे ही सबसे उपेक्षित रहती हैं. राजस्थान के बीची उपकेंद्र की पुष्पा सिसोदिया के जिम्मे आठ से दस किमी क्षेत्र में फैले 12 गांव हैं. अगर उन्हें अपना काम ठीक से करना हो तो उन्हें बच्चे का वजन मापने वाली मशीन, टेप और खून की जांच करने वाले उपकरण हमेशा साथ लेकर चलना होगा. इसीलिए उन्हें यही आसान लगता है कि वे इस इंतजार में बैठी रहें कि गर्भवती महिलाएं उनके पास आएं. मगर ऐसा सिर्फ 20 फीसदी महिलाएं ही कर पाती हैं.

पुष्पा तो अपने उपकेंद्र पर रहती भी हैं. लेकिन अधिकांश दाइयां अपने केंद्र के पास के शहरों में रहना ही पसंद करती हैं. शहर से आने वाली इन औरतों को गांव वाले अपने से थोड़ा अलग ही मानते हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और फिर वे रोज-रोज की पूछताछ वगैरह के लिए उपलब्ध भी नहीं रहतीं. जन्म के समय अगर बच्चे को कुछ हो गया तो फिर उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है. इन दाइयों को प्रशिक्षण देने और उन्हें सस्ते और साधारण प्रसूति सामग्री देने की बात भी थी लेकिन अभी तक इस मामले में कोई पहल नहीं हुई है. डॉ. रामेश्वर शर्मा कहते हैं, "कागज पर तो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था प्रभावशाली लगती है. लेकिन असलियत में यह काम ही नहीं कर पाती."

बच्चों के अस्तित्व की रक्षा के मामले में सरकार के सामने भारी चुनौती है व्यापक टीकाकरण की. लक्ष्य है 1990 तक 70 फीसदी शिशुओं को मौत के मुंह में जाने से बचा लेने का. सभी स्वास्थ्य केंद्रों तक इन टीकों को पहुंचाने का मतलब है इन्हें रखने के लिए वहां फ्रिज की व्यवस्था भी करना. और फिर अधिकांश केंद्रों में बिजली कुछ ही घंटों के लिए आती है. ऐसे में फ्रिज भी काम नहीं करेंगे. अगर पोलियो और डीपीटी के टीकों को कम तापक्रम पर नहीं रखा जाए तो वे असरकारक नहीं रह जाते. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक बद्री सक्सेना बताते हैं, "यह बहुत निचले स्तर तक पहुंचने का कार्यक्रम है. अगर इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता ठीक से नहीं लगते, तो कितना भी अच्छा संगठन क्यों न हो, कामयाबी नहीं मिल सकती. मुझे लगता है कि हम मातृ और शिशु कल्याण के व्यापक कार्यक्रम में पीछे छूट गए हैं."

फरेब नं. 6

"महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्हें पराधीनता और असुरक्षा से मुक्त करने और उनका सामाजिक दर्जा बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा."

—छठी योजना का दस्तावेज, 1980

सचाई: महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा गांव की प्रभा सदाशिव ने 16 वर्ष की उम्र में विवाह करने से मना कर दिया और बीकॉम की डिग्री लेना ही अधिक महत्वपूर्ण माना. पिछले साल उनकी शादी एक मिल के सुपरवाइजर से हुई और अब उनको एक बेटा भी है. वे खुद एक स्वास्थ्य केंद्र पर गईं और कॉपर-टी लगवा लिया. वे कहती हैं, "मैं केवल दो बच्चे चाहती हूं. मैं उनका लालन-पालन ठीक से कर सकती हूं और अब मैं जल्दी ही बैंक में नौकरी शुरू करने जा रही हूं."

प्रभा के मामले से साफ है कि साक्षरता का लड़कियों की शादी की उम्र, बच्चों की संख्या और उनके जन्म के बीच फासला तय करने पर कितना अच्छा असर पड़ता है. यह तथ्य राजस्थान के उदाहरण से भी स्पष्ट होता है जहां महिलाओं में साक्षरता सबसे कम (6.4 फीसदी) है और इस कारण उनके विवाह की औसत उम्र भी सबसे कम—16.1 वर्ष—है. केरल की औरतों में साक्षरता सबसे ज्यादा—72 फीसदी—है और वहां उनके विवाह की औसत उम्र सबसे ज्यादा—21.9 वर्ष—है.

अभिभावकों को अपनी बेटियों की शादी देर से करने के लिए राजी करना टेढ़ी खीर है. यह बात अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मानने लगे हैं. समाजशास्त्रियों का कहना है कि अब दूल्हों का 'अकाल' भी पड़ता जा रहा है. और लड़कियों की भरमार होने से उनकी शादी जल्दी-से-जल्दी निबटाने की कोशिश की जाती है. विवाह योग्य प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1168 हो चुकी है.

यह एक दुष्चक्र बनता जा रहा है. मां-बाप अपनी बेटियों को हाई स्कूल के ऊपर पढ़ाना नहीं चाहते. इस कारण भी वे कभी नौकरी पाकर आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकतीं. चूंकि लड़कियां आर्थिक रूप से बोझ बन जाती हैं और मां-बाप को डर रहता है कि वे 'बिगड़' न जाएं, इसलिए भी वे उनकी शादी झटपट कर देना चाहते हैं. कम उम्र में शादियां आज भी जारी हैं क्योंकि लोगों के सामने अब भी इसका कोई अच्छा विकल्प नहीं है. वैसे, औरतों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना एक तरीका हो सकता है.

फरेब नं. 7

"हर स्तर के जन प्रतिनिधियों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता होनी चाहिए."

—जनसंख्या और विकास पर भारतीय सांसद संघ की घोषणा, 1981

सचाई: जनसंख्या की समस्या के मामले में इतनी निराशाजनक स्थिति के पीछे एक बड़ा कारण है दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव. संजय गांधी के जमाने में हुई ज्यादती और उसके राजनैतिक कुप्रभावों के बाद हर नेता 'नसबंदी' शब्द से ही हड़कता है. छह साल पहले बने जनसंख्या और विकास पर भारतीय सांसद संघ के अध्यक्ष सतपाल मित्तल कहते हैं, "इस कार्यक्रम से सांसद तो ऐसे डर गए जैसे कोई हौवा हो. परिवार नियोजन कार्यक्रम बड़े बेमन से चलाया जा रहा है और कोई स्पष्ट उद्देश्य और इच्छाशक्ति नही दिखाई देती. इतना अपार बहुमत पाने के बाद भी राजीव गांधी अगर कड़े कदम नहीं उठा सकते तो और कोई नहीं कुछ कर सकता."

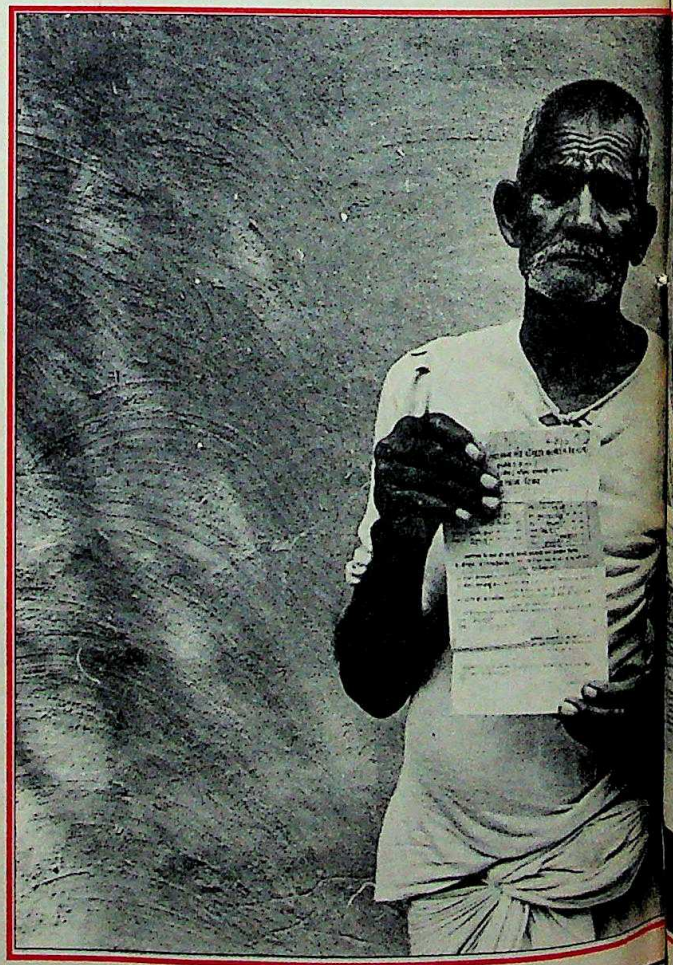

उत्तर प्रदेश के 80 वर्षीय छोटेलाल और उनका बेटा 40 वर्षीय लक्ष्मण: पैसे के लिए दुबारा नसबंदी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फरेब नंबर 4

सरकार कहती है वह सुविधाएं देने के मामले में बड़ा परिवार रखने वालों से सख्ती बरतने की सोच रही है

लेकिन उसने अपने कई सख्त उपायों को लागू करने में राजनैतिक संकल्प शक्ति का परिचय नहीं दिया है

...और सचाई

लेकिन सरकार के 'कड़े कदमों' का कोई ठोस नतीजा नहीं दिख रहा. सुझाव यह भी था कि परिवार के आकार के आधार पर ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कर्ज दिए जाएं. बड़े परिवारों को कर्ज ही न दिया जाए. ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव इंदरजीत खन्ना बताते हैं, "हम लोग छह बच्चों वाले परिवार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से बाहर कैसे कर सकते हैं जबकि उन्हीं को सबसे अधिक मदद की जरूरत है."

परिवार नियोजन कार्यक्रम में देश की 94,000 ग्रामीण सहकारी समितियों को लगाने की योजना पर प्रभावी ढंग से अमल गुरू ही नहीं हो सका. करीब साल भर पहले प्रमुख सहकारी संगठनों के प्रमुखों की बैठक में इस योजना की घोषणा की गई थी. ग्रामीण विकास विभाग के एक बड़े अधिकारी कहते हैं, "हर आदमी ने इसे सुना, मोटी सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर इसे बिसार दिया. घोषणा के बाद कुछ नहीं हुआ. अन्य विभागों के रवैये से तो यही लगता है कि भारत चीन जैसी उपलब्धियां नहीं हासिल कर सकता. चीन ने एक बच्चे से अधिक की सीमा को तोड़ने वालों को भारी दंड देने की व्यवस्था की थी. जनसंख्या अध्ययन संस्थान के श्रीनिवासन का मानना है कि "लोकतंत्र में सख्ती नहीं चल सकती. हर पांच साल बाद चुनाव मैदान में उतरने वाले नेता दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखा सकते." सरकार ने इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के मामले में सख्ती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी. नए स्वास्थ्यमंत्री मोतीलाल वोरा मानते हैं, "कड़े कदमों के लिए स्थायी व्यवस्था करनी होती है. अभी तो लोगों को समझाने-बुझाने और शिक्षित करने की जरूरत है. आम तौर पर जो परिवार जितना ही गरीब होता है, सदस्यों की संख्या उतनी अधिक होती है."

फरेब नं. 8

"सन् 1990 तक हमें प्रति हजार 29 और सन् 2006 तक 21 की जन्म दर पर पहुंचना चाहिए."

—योजना आयोग

सचाई: भारत की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि 13.7 करोड़ दंपतियों को दो ही बच्चे पैदा करने पर राजी किया जाए. जनसंख्याविदों की भाषा में इसे संतानोत्पत्ति दर घटाकर एक पर करना कहते हैं. ऐसा करने के लिए सरकार को सन् 2006 तक प्रति हजार लोगों पर जन्म दर 21 पर लाना होगा. साथ ही जन्म दर में वृद्धि की दर 2.2 फीसदी से घटाकर 1.2 फीसदी पर लाना होगा. अपेक्षित दर 1995 तक ही हासिल कर लिया जाना है. पर यह समय सीमा बढ़ती ही जा रही है.

अब जन्म दर एक बिंदु पर स्थिर हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव के माथे पर पड़ी बलें भी स्थिर हो गई हैं मानो. वे कहते हैं, "हम यही मानते रहे हैं कि जनसंख्या की बाढ़ बेकाबू नहीं होगी. लेकिन असलियत यह है कि इस पर कभी नियंत्रण करने की कोशिश ही नहीं हुई. 1990 तक प्रति हजार आबादी पर 29 की जन्म दर हम हासिल नहीं कर सकते."

जो मंत्रालय अब तक अपनी असफलताओं को छिपाने में बहुत धूर्तता और सावधानी बरतता रहा है उसमें उमाशंकर जैसे अधिकारी बदलाव का एहसास कराते हैं. उनके लिए आलोचना से बच जाना महत्वपूर्ण नहीं है. समस्याओं को रेखांकित करना उनके लिए महत्वपूर्ण बात है. वे कहते भी हैं, "आबादी की समस्या ऐसी है जिसमें सभी प्रमुख मंत्रालयों को शामिल होना चाहिए."

उमाशंकर की बातों से अधिकांश जनसंख्याविद सहमत हैं. परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू होने के दिनों से ही इससे जुड़े रहने वाले पुणे के भानु कोमाजी कहते हैं, "हमें यह एहसास होना चाहिए कि संतति निरोध कोई तकनीकी मामला नहीं है. यह बहुत ही मानवीय और संवेदनशील समस्या है और इसका इसी दृष्टिकोण से समाधान ढूंढ़ना चाहिए. इसे जन-आंदोलन का रूप देना होगा."

अधिक गड़बड़ी इस कार्यक्रम से जुड़ी लालफीताशाही के कारण हुई है. स्वास्थ्यमंत्री वोरा मानते हैं कि केंद्र द्वारा लक्ष्य तय करने से "लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि यह केंद्र का कार्यक्रम है, केंद्र के ही फायदे के लिए है और केंद्र ही इसे चला रहा है." इस कार्यक्रम में विकेंद्रीकरण का कोई तत्व नहीं है और अब जाकर राष्ट्रीय लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में राज्यों की राय भी पूछी जाने लगी है.

जन्म दर के स्थिर रहने से चिंता तो व्याप्त है ही, लेकिन अगर कुछ किया नहीं गया तो इस दर में बढ़ोतरी भी शुरू हो सकती है.

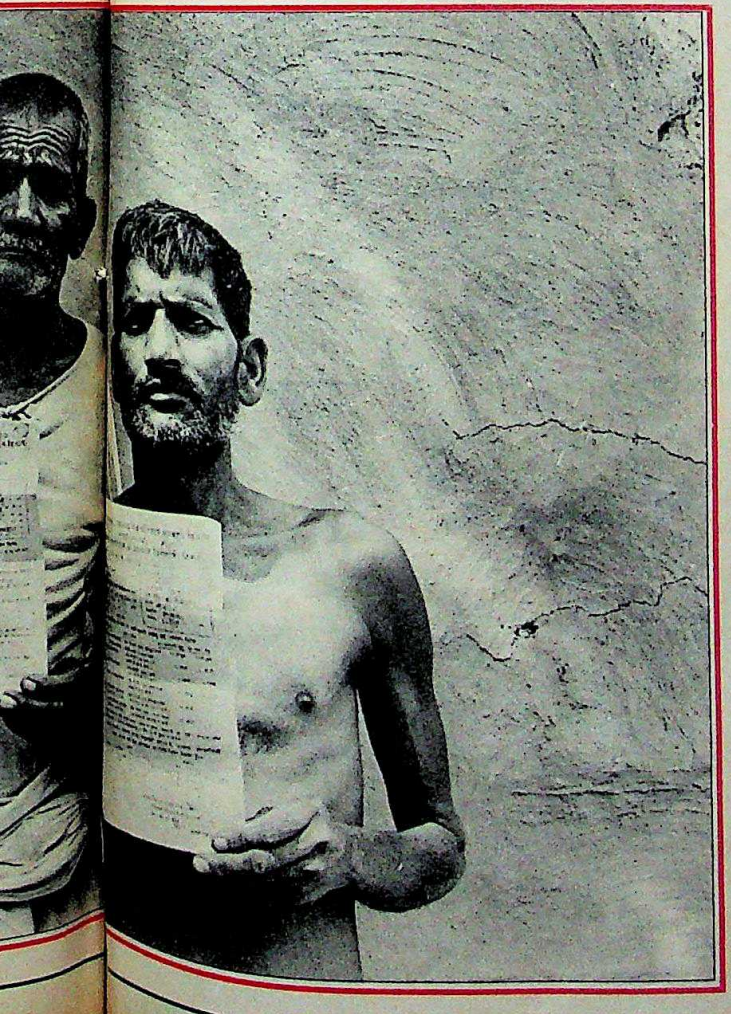

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशेष छूट

हिंदी पाठकों के लिए
इंडियन एक्सप्रेस वर्गीकृत विज्ञापनों पर
वैवाहिक, रिक्त स्थान / नौकरी चाहिए
(टेलेंट बैंक) तथा अन्य वर्गीकृत विज्ञापनों पर

कृपया ध्यान रखें

१) आप का विज्ञापन अगले रविवार को प्रकाशनार्थ बुधवार प्रातः १० बजे से शाम ४ बजे तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। किसी अन्य दिन प्रकाशन हेतु, अपना विज्ञापन, कृपया तीन दिन पूर्व दें।
२) अपना विज्ञापन नीची दी गई तालिका में केवल स्पष्ट अक्षरों में लिखें।
३) कृपया अपना कूपन दो प्रतियों में भेजें। आप दूसरी प्रति के लिए सादे कागज का प्रयोग कर सकते हैं।
४) आप अपना विज्ञापन हिंदी अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। ट्रांसलेशन की सुविधा निशुल्क है।
५) संतोषप्रद उत्तर न मिलने पर आपका विज्ञापन हमारे अन्य प्रकाशनों में निशुल्क छापा जाएगा।
६) यह सुविधा ३-७-८८ से लागू है।

इंडियन एक्सप्रेस व जनसत्ता (दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए दरें)	इस कूपन पर
रु. ६ प्रति शब्द	रु. ३ प्रति शब्द

कृपा ध्यान दें:— इस कूपन पर बाक्स प्रभार (जहां कहीं अपेक्षित हो) हमारी नियमित दर रु. २०/- के स्थान पर रु. १०/- रहेगी।
इंडियन एक्सप्रेस व जनसत्ता सजावटी वर्गीकृत विज्ञापन दर रु. ७०/- प्रति कालम सेमी रहेगी।

इंडियन एक्सप्रेस
९-१० बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-११०००२

केवल तीस दिन की अवधि के लिए वैध
नकद राशि केवल व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली प्रवष्टियों के साथ ही स्वीकार की जाएगी।

कृपया हर खाने में एक शब्द लिखें

नाम: ----------

पूरा पता: ----------

प्रकाशन तिथि: ----------

हस्ताक्षर: ----------

SAV/88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जन्म दर को ऊपर उठाने वाली जो प्रवृत्तियां अभी दिख रही हैं उनमें से एक तो है परंपरागत आदतों का छूटते जाना. शहरीकरण बढ़ते जाने से उन आदतों पर अब कोई ध्यान नहीं देता. जनसंख्याविदों का मानना है कि 60 और 70 के दशक में जो बच्चे बिना रोक-टोक पैदा हो गए थे वे अब खुद संतान उत्पन्न करने वाली अवस्था में पहुंचने लगे हैं. टाटा द्वारा संचालित परिवार नियोजन संस्थान के कार्यकारी निदेशक हरीश खन्ना कहते हैं, "लगता है कि बच्चों की बाढ़ का दूसरा दौर तो बस अब आने ही वाला है."

फरेब नंबर 5

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि आबादी में बढ़ोतरी की दर सन् 2001 तक स्थिर हो जाएगी

लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के कई अधिकारियों का मानना है कि यह असंभव ही है

...और सचाई

तो अब सवाल यह है कि क्या भारत अब भी अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगा सकता है या अब बहुत देर हो चुकी है?

उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा बहुत आसान उपाय बताते हैं, "हमें इसे राष्ट्रीय चिंता का मुद्दा बनाना होगा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता." हर आदमी उनकी इस बात से सहमत है लेकिन समस्या के समाधान के तरीकों पर मतभेद हैं. पाणंदीकर का मानना है कि विकास ही सबसे कारगर गर्भ निरोधक का काम कर सकता है. वे कहते हैं, "अब उम्मीदें तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग पर ही टिकी हैं. यह वर्ग ही आर्थिक तरक्की की गति तेज करेगा और जनसंख्या के मामले में बदलाव लाएगा."

लेकिन कई विशेषज्ञों समेत उमाशंकर भी इस राय से सहमत नहीं हैं. वे कहते हैं, "असली सवाल यह है कि क्या हम इन्हें लागू होने तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं. हमें भगवान बनने का स्वांग रचना भी पड़े तो वह भी बहुत संयमित ढंग से करना होगा."

नवजात शिशुः अनिश्चित भविष्य

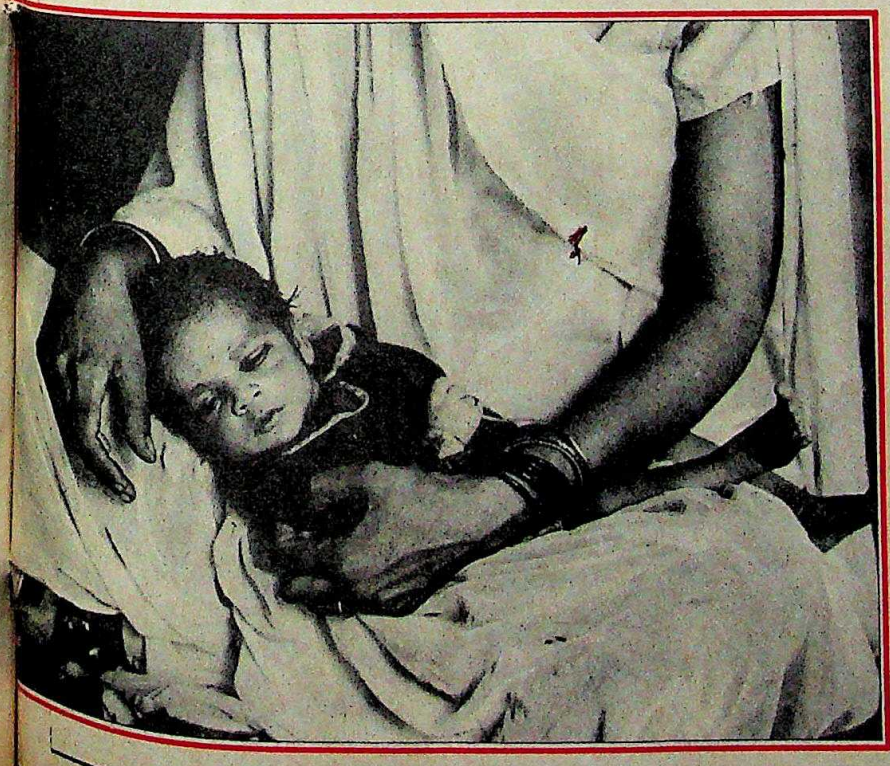

उनका मानना है कि सरकार द्वारा छोटे परिवारों को भारी प्रोत्साहन देने के साथ-साथ इन कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू करना ही इस समस्या का असली समाधान हो सकता है.

कई लोगों का मानना है कि सरकार का लक्ष्य जन्म दर को कम करना न होकर सभी जोड़ों के लिए प्रभावी और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन मुहैया कराना होना चाहिए. लक्ष्य तय करने का फैसला विकेंद्रित होना चाहिए और इसमें राज्यों की भूमिका बढ़नी चाहिए. साथ ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए. कई लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में देश भर में फैले संगठनों को शामिल करना चाहिए. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तो स्वयंसेवी संगठनों को ही सौंप देना चाहिए. बोस का मनाना है कि बेरोजगारी वाले पहलू पर भी अधिक ध्यान देना होगा. एक से अधिक बेटे की इच्छा के बारे में पुणे के किसान जगताप कहते हैं, "मैं जानता हूं कि मेरी जमीन रबर की तरह फैलाई नहीं जा सकती. और बंटवारे के बाद सभी बेटों को पर्याप्त जमीन नहीं मिलेगी." बोस कहते हैं, "लोग बेरोजगारी वगैरह की मोटी बातें जल्दी समझ जाते हैं. सुखी और स्वस्थ परिवार की हवाई परिकल्पनाएं उनके मन में नहीं बैठ पातीं."

महिलाओं को शिक्षण और रोजगार मुहैया कराने की हवाई बातें ही नहीं, उन्हें ठोस रूप देने की कोशिश होनी चाहिए, खासकर 'बिमारू' राज्यों में. युवतियों के लिए प्रशिक्षिण शिविर लगाने और उनको अपनी कुशलता बढ़ाने में मदद देने के सुझाव पर गंभीरता से अमल करना होगा. अनेक गांवों में मृतप्राय महिला मंडलों को फिर से सक्रिय करने से भी लाभ होगा. इस प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

संक्षेप में कहें तो जनसंख्या नियंत्रण की चिंता हर किसी को होनी चाहिए. लेकिन फिलहाल कार्यक्रमों और उन्हें लागू करने के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है. अगर तेजी से कुछ नहीं किया गया तो शायद गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में राजीव के 21वीं सदी के भारत के बारे में कुछ इस तरह लिखा जाएगा —

सर्वाधिक जनसंख्या वाला देशः भारत (जनसंख्या 1.2 अरब); दुनिया का हर पांचवां आदमी भारतीय; प्रति सेकेंड एक बच्चे का जन्म; हर दिन 86,400 बच्चे.

सर्वाधिक गरीब देशः भारत (प्रति व्यक्ति औसत आय: 3000 रु.)

सर्वाधिक अनपढ़ों वाला देशः भारत (अनपढ़ों की संख्या: 60 करोड़).

सर्वाधिक बेरोजगारों वाला देशः भारत (बेरोजगारों की संख्या: 40 करोड़).

सर्वाधिक बेघरों का देशः भारत (बेघरों की संख्या: 60 करोड़).

—**राज चेंगप्पा,** उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान

कन्या के कत्ल की कुप्रथा

भैरों सिंह शेखावत की अगुआई में राज्य के विपक्षी दलों ने पिछले पखवाड़े जब एक इंकाई विधायक पर नवजात कन्या की हत्या का आरोप मढ़ा तो लोग स्तब्ध रह गए और उस पर काफी हो-हल्ला मचा. इस आरोप के बाद ऐसी संगठित हत्याओं के कई मामले सामने आ गए. वरिष्ठ संवाददाता पंकज पचौरी ने यह जानने के लिए राज्य के दूरदराज के इलाकों का दौरा किया कि क्या यह अमानुषिक प्रथा बड़े पैमाने पर जारी है. उनकी रिपोर्ट:

थार के निर्मम रेगिस्तानी क्षेत्र में 81 वर्षीया धापू एक बहुत ही होशियार दाई के रूप में विख्यात हैं. बैया गांव और आसपास के इलाकों में प्रसव कराने वाली वही एकमात्र नर्स हैं. क्योंकि सबसे नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी 60 किमी दूर है, और एकमात्र अस्पताल 150 किमी दूर जैसलमेर में है. इस इलाके में कोई सड़क नहीं है फिर भी धापू की प्रसिद्धि बालू के ढूहों को पार करती दूरदराज के भाटी राजपूतों के गांवों तक पहुंच गई.

हर पखवाड़े उन्हें कहीं-न-कहीं प्रसव करवाने के लिया बुलाया जाता है. घर की औरतें अपने रंगारंग परिधानों में आंगन में जमा रहती हैं. लेकिन यदि घर किसी भाटी का है और नवजात शिशु कन्या है तो धापू कुछ सेकेंडों में ही काम निबटाकर चल देती हैं. और नवजात शिशु के आगमन पर गाए जाने वाले गीत नहीं सुने जाते. उसके बाद जो कुछ होता है वह एक नितांत घिनौनी प्रथा है. इन सबकी आदी हो चुकीं धापू इसे 'बुरी

सभी फोटो: प्रशांत पंजियार

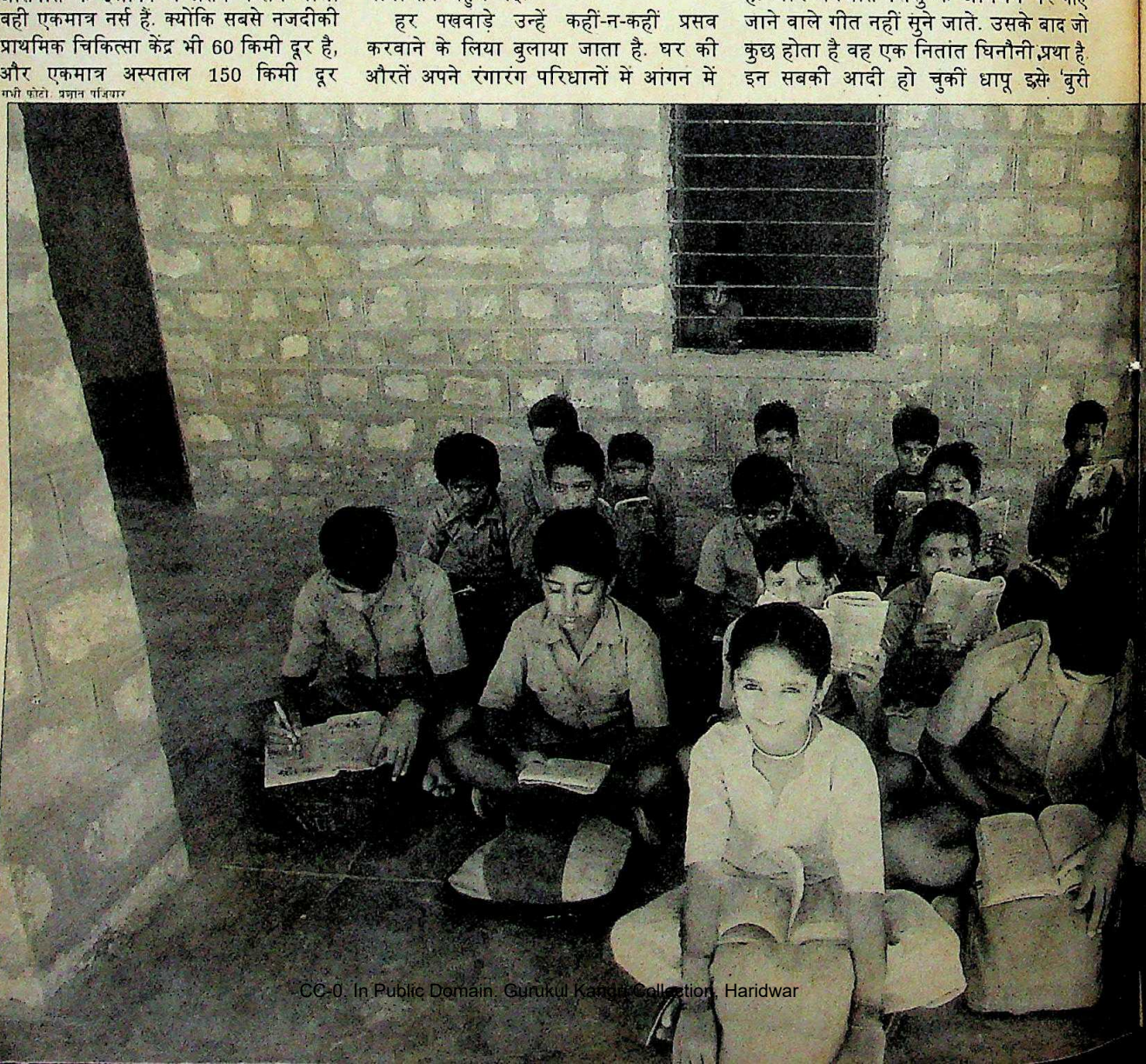

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रथा' कहती हैं. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में इसे 'हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव-वध' कहा गया है.

भाटी राजपूतों के समुदाय में नवजात कन्याओं की हत्या की कुप्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है. हत्या के तरीके भी इस कुप्रथा की तरह बर्बर और आदिम हैं. शिशु का दम घोंटने के लिए बालू भरी बोरी उसके मुंह पर डाल दी जाती है या फिर अफीम की बड़ी खुराक दे दी जाती है. यदि ये दोनों उपाय नाकाम होते हैं तो सीधे-सीधे उसका गला घोंट दिया जाता है. आश्चर्य यह है कि यह सब कुछ खुद उसकी मां करती है और दूसरी महिलाएं उसे इस अवांछित शिशु से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करती हैं. इस प्रथा के नतीजे जितने दुखद हैं उतने ही नाटकीय भी. इस इलाके की आबादी में अब हर 1000

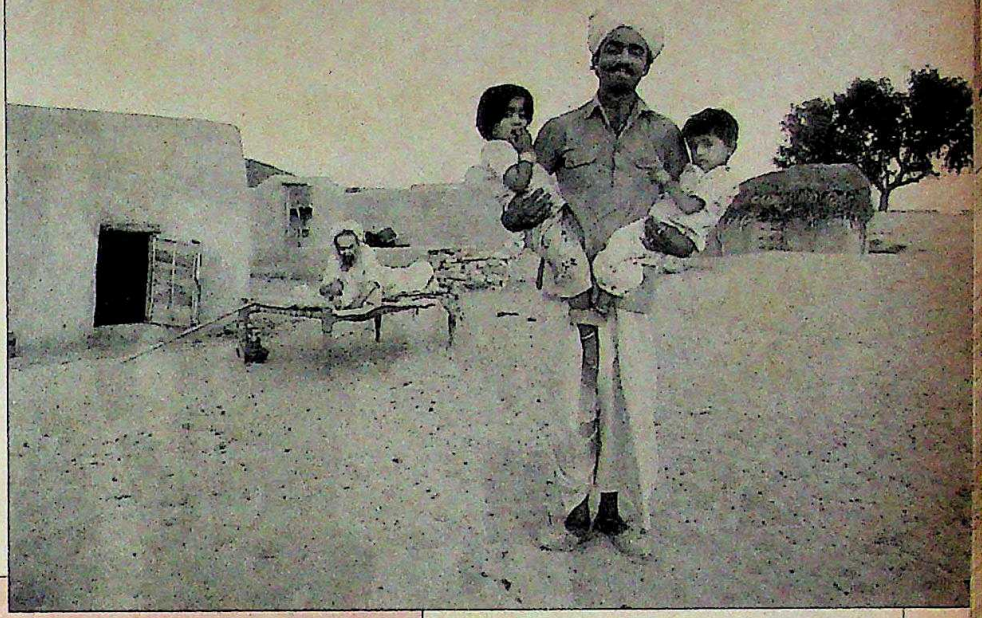

▲ बैया के शिक्षक सायर सिंह इस प्रथा के विरोधी हैं और उन्होंने अपनी दो भतीजियों की जान बचाई

▼ नौ वर्षीया जयवंत कंवर देवरा गांव की उन दो लड़कियों में से एक है जो हत्यारी प्रथा से बच गई है

पुरुष पर 750 महिलाएं हैं, जबकि देश में यह संख्या 938, राजस्थान में 919 और भाटीबहुल जिले जैसलमेर में मात्र 811 है. लेकिन पूरे भाटी समुदाय में यह संख्या शायद दुनिया में सबसे कम करीब 550 ही है.

जैसलमेर जिले की पश्चिमी सीमा पर बसे करीब एक दर्जन गांवों में भाटी लड़कियों की संख्या मुश्किल से 50 है जबकि कुल आबादी 10,000 से भी अधिक है. सभी लड़कियां दस साल से कम उम्र की हैं. इससे पता चलता है कि यह प्रथा अब धीरे-धीरे बदलने लगी है. और अब सभी भाटी अपनी नवजात कन्याओं की हत्या नहीं करते. किसी भाटी के यहां लड़की के लिए बारात आखिरी बार कब आई थी, इस सवाल पर यहां के लोग दशकों में ही अंदाज लगाते हैं.

बैया से करीब 50 किमी दूर देवरा प्राथमिक विद्यालय के कुल 175 बच्चों में सिर्फ 9 वर्षीया जयवंत कंवर ही एकमात्र भाटी छात्रा है. वह कक्षा में पहली पंक्ति में बैठती है जिसमें उसके अलावा सभी लड़के ही होते हैं. दिलचस्प बात तो यह है कि गांववालों के बीच कहावत चल पड़ी है कि जयवंत किसी देवी की अवतार है. गांववालों ने कहा, "इसी वजह से वह जिंदा है, नहीं तो वह भी औरों की राह चली गई होती." उसके पिता पन्ना सिंह ने कहा कि प्रधान बनने के बाद वे शहर गए और उसके बाद उन्होंने इस प्रथा को तोड़ने का फैसला किया.

गांववालों ने 'इंडिया टुडे' को बताया कि पिछले साल अकेले बैया गांव में ही 16 नवजात कन्याओं की हत्या की गई. मोटे अनुमान के अनुसार इन 12 गांवों में हर साल ऐसी करीब 150 हत्याएं होती हैं. यह सब ऐसे राज्य में हो रहा है जहां 'शिशु, महिला और पोषण' नाम से एक नया विभाग कायम किया गया है.

शताब्दियों पुरानी इस कुप्रथा के पीछे कई कारण जुड़े हुए हैं—सरकारी लापरवाही, अज्ञानता, अंधविश्वास, दहेज और सबसे ऊपर भाटियों की झूठी सामंती शान. जैसलमेर राज्य की पुरानी शासक जाति जब समय बीतने के साथ बिखरने लगी तब इसका रेगिस्तानी जीवन की मुश्किलों से सामना हुआ. भाइयों में बंटवारा हो गया. मवेशी, खेत बंट गए. सोने का भंडार छीजने लगा. लेकिन भाटियों की शान में कमी नहीं आई.

लेकिन भाटी ऐसी माटी के बने हैं जो समझौता करना नहीं जानते. जैसलमेर के जिला प्रमुख भोपाल सिंह अपने समुदाय के मानस का सही विश्लेषण करते हैं, "हम भीख नहीं मागेंगे, डकैती करना मंजूर है." भाटियों में अपने पड़ोसियों और बिरादरी के अन्य लोगों को नीचा दिखाने की सनक भी बची रह गई है. लेकिन जीवन जल्द ही विकट बन गया. दूसरों के सामने अपना सिर नीचा करने और दूल्हों की तलाश में भटकने के बदले भाटियों ने अपनी बेटियों का सिर कलम करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें डर था कि वे उनकी मुसीबत बन सकती हैं. देवरा गांव के पूर्व प्रधान चतुर सिंह ने माना, "हम जानते हैं कि यह ठीक नहीं है पर दहेज में देने के लिए सोना किसके पास है? इसी कारण हमें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह सब करना पड़ रहा है.''

पिछले 24 साल से लगातार प्रमुख रहे और जैसलमेर के 2.5 लाख लोगों का इंका के टिकट पर राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके भोपाल सिंह के अनुसार 50 साल पहले यहां नवजात कन्याओं की हत्या एक आम प्रथा थी. लेकिन इस बीच बाकी दुनिया के लोगों से हेलमेल से स्थितियां बदली हैं. जैसलमेर से 30 किमी दूर बरौरा गांव के जैत सिंह ने माना, ''अब सब कुछ तेजी से बदल रहा है. 25 साल पहले इस गांव में एक दर्जन से भी कम लड़कियां थीं. अब लोग लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल की मांग करने लगे हैं.''

▲ बैया की 15 वर्षीया पवन की शादी अगले साल होगी तो वहां दशकों बाद बारात आएगी

भारतीय कल्याणकारी राज्य की सभी विकास योजनाएं जिले की पश्चिमी सीमा के इस अंधेरे कोने तक अभी भी नहीं पहुंची हैं. सरकार शिक्षा पर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 16.74 रु. खर्च करती है. इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि पढ़ और लिख सकने वाले लोगों को उंगली पर गिना जा सकता है. नवजात कन्याओं की हत्या जहां बदस्तूर जारी है, उन गांवों—देवरा, बैया, झिझियाली, मांधा, रांधा और कुंडा—में साक्षरता 12 फीसदी है. 4,901 की कुल आबादी में सिर्फ 15 महिलाएं ही प्राथमिक स्तर तक पढ़ी हैं.

बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त करना भी काफी मुश्किल काम है. दो छोटे शहरों और 522 गांवों के बीच सिर्फ 139 डाकघर और 160 डाकपेटियां ही हैं. सिर्फ 86 गांवों में ही बिजली पहुंची है. पक्की सड़क की लंबाई सिर्फ 529 किमी ही है. इस कारण 80 फीसदी से अधिक आबादी पहुंच के बाहर है. जिला कलेक्टर अशोक जैन मानते हैं कि ऐसी कुप्रथा विकास के जरिये ही मिटाई जा सकेगी पर विकास कार्यों के लिए संसाधनों की खासी कमी है.

जैत सिंह का कहना है कि महज एक बुनियादी व्यवस्था करके यानी प्रसूति वार्ड वाला एक अस्पताल बनाकर भी इस कुप्रथा पर बहुत अंकुश लगाया जा सकता है. शिशु के लिंग का पता चलते ही बाकी औरतें मां को लड़की से निजात पाने के लिए समझाने-बुझाने लगती हैं. इस डर से कि कहीं बच्चा रोने न लगे और उसके आगमन की सूचना पड़ोसियों तक न पहुंच जाए, प्रसव होने के मिनटों के भीतर ही उसका काम तमाम कर दिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है गर्भपात हो गया. परंपरा के अनुसार दूसरे लोग बच्ची की हत्या नहीं करते. यह अपराध मां को ही करना पड़ता है. ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि शिशु के जन्म के बाद मां घंटों तक बेहोश रही और कन्या बची रह गई. जैत सिंह कहते हैं, ''अस्पताल में यदि बच्ची एक-दो दिन जिंदा रह जाती है तो कोई उसकी हत्या की नहीं सोचेगा.'' एसपी सुधीर प्रताप सिंह ने माना कि यह कुप्रथा व्यापक है पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि एक 'बंद' समुदाय में व्याप्त परंपराओं के कारण राज्य प्रशासन 'असहाय' हो जाता है.

दूसरी बुनियादी जरूरत है स्कूल. इससे इस कुप्रथा के प्रति लोगों को निरुत्साहित करने में मदद मिलती है. गांवों में इस कुप्रथा के विरुद्ध बोलने वालों में शिक्षक ही प्रमुख हैं. बैया में 26 वर्षीय सायर सिंह इस मुद्दे पर गांव के बुजुर्गों की बैठक बुलाने की कोशिश कर चुके हैं. इसमें उन्हें सफलता तो अधिक नहीं मिली पर इससे उनका जोश ठंडा नहीं पड़ा है. अपनी भतीजी होशियार कंवर को पुचकारते हुए उन्होंने कहा, ''अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि उनके सामने उदाहरण पेश करूं. मैं अपनी बेटियों को घर में पालूंगा; उन्हें स्कूल भेजूंगा और संभव हुआ तो नौकरी करने के लिए भी भेजूंगा. तभी ये लोग समझ सकेंगे.''

झिझियाली में 32 वर्षीय रेवात सिंह समुदाय के लोगों को अपना झूठा अहं त्यागने की सलाह देते हैं और दहेज की बुराई के बारे में उन्हें शिक्षित करते हैं. 1972 में जब उनकी बहन की शादी हुई थी तो उन्होंने दहेज को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया था. उनका यह निश्चित तौर पर मानना है कि लोगों के दिमाग से जब परदा उठेगा तब उन्हें अपने अज्ञान का पता चलेगा. रेवात कहते हैं, ''हमें एक सड़क और गांव तक बस सेवा की जरूरत है. इससे लोग शहरों में जाएंगे और एक नई दुनिया से उनका परिचय होगा.''

लेकिन यह आसमान से तारे तोड़ने के समान ही है. बैया में लोगों ने जीप आखिरी दफा तब देखी थी जब तीन साल पहले राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार के लिए शहरों से लोग आए थे. यहां से नजदीकी बस स्टॉप भी 20 किमी दूर है. देवरा से पहली बस इस साल अगस्त में चली. देश आजादी के 41वें वर्ष का जश्न मना रहा है, मौसम का मिजाज जानने के लिए उपग्रह भेजे जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली की दीवारें मानवाधिकार के लिए रॉक नृत्य करने वाले कलाकारों के आगमन के पोस्टरों से अटी पड़ी हैं, लेकिन दूसरी ओर रेवात और सायर भी हैं जो आज भी यही इंतजार कर रहे हैं कि काश उनके गांव तक कोई बस आने-जाने लगे ताकि गांव के लोग इस अंधेरे से निकल सकें.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

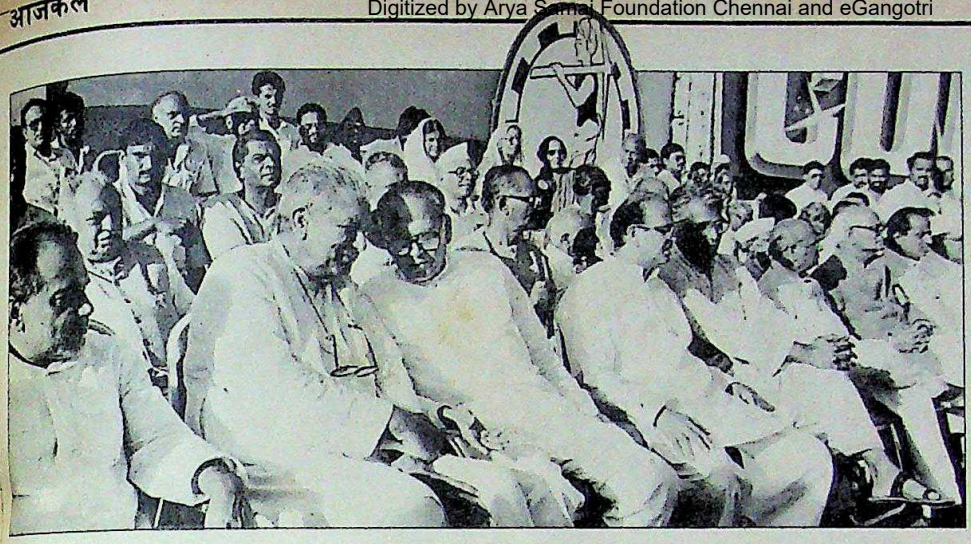

मंच पर वी.पी. सिंह और दूसरे नेता: एका हुआ

विपक्षी एकता

औपचारिकता पूरी हुई

'जनता दल' का चार में एक घटक गठन से पहले ही बाहर

विपक्षी खेमे में एकता के सवाल पर महीनों चली ले-दे के बाद बंगलूर में तीन मध्यमार्गी विपक्षी दलों के विलय से जनता दल बनाने की औपचारिक घोषणा आखिर कर दी गई.

बंगलूर पैलेस के मैदान में हुए नई पार्टी के स्थापना सम्मेलन ने, जैसी कि उम्मीद थी, सर्वसम्मति से विश्वनाथ प्रताप सिंह को अध्यक्ष चुना. इस बारे में प्रस्ताव पेश करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने कहा भी, "आपको मालूम ही है अध्यक्ष कौन होगा? हम तो औपचारिकता भर पूरी कर रहे हैं."

लेकिन कई और औपचारिकताएं बाकी रह गईं जिन्हें पूरा करने के लिए सम्मेलन ने एक महीने का समय दिया है. नाम, झंडे, चुनाव चिन्ह वगैरह के मामले निबट जाने के बावजूद सम्मेलन में कई प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति रहस्यमय रही. इनमें जन-मोर्चा संयोजक रामधन, लोकदल अध्यक्ष हेमवतीनंदन बहुगुणा और कांग्रेस (स) के महासचिव के.पी. उन्नीकृष्णन के नाम उल्लेखनीय हैं.

सम्मेलन में कांग्रेस (स) के कुछ प्रतिनिधि मौजूद रहने के बावजूद पार्टी आखिरी समय में विलय के सवाल पर पीछे हट गई. इसके पीछे असुरक्षा की भावना काम कर रही थी. हालांकि पार्टी का कहना था कि उसे कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए ज्यादा समय की जरूरत है पर असलियत यह है कि उसके नेता नई पार्टी में मिलने वाली छोटी भूमिका से नाराज थे.

इधर सम्मेलन चल रहा था, उधर उन्नीकृष्णन एलान कर रहे थे, "इस महीने के अंत में हमारी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी." पर बाद में उन्नीकृष्णन ने कहा कि वे 'वी.पी. सिंह द्वारा प्रस्तावित बातचीत में हिस्सा लेंगे' पर उन्होंने जनता दल का जिक्र कांग्रेस (स) के नजदीकी मित्र के तौर पर किया. बहुगुणा ने भी 'विपक्षी एकता में बाधा नहीं' बनने का एलान किया.

विपक्षी एकता कितनी कारगर रहेगी, यह तो समय ही बताएगा पर वी.पी. सिंह को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी. उन्हें एहसास हो गया लगता था कि दिलेरी दिखाने का वक्त आ गया है, वरना राजनैतिक भविष्य अंधकार-मय हो जाना निश्चित है.

स्थापना सम्मेलन शुरू होने के एक दिन पहले तक विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई चल रही थी. वी.पी. सिंह ने विपक्षी एका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जनमोर्चा को वस्तुतः भंग कर दिया था जिस पर उनके सहयोगी अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां और रामधन बहुत नाराज हो गए थे. उन पर एक नई पार्टी बनाने की घोषणा करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था.

उन्होंने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की हर तरह से कोशिश की. विलय को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने पहली बार एक 17 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया. एका के रास्ते में सबसे बड़े बाधक बहुगुणा और चंद्र-शेखर को इसका सदस्य बनाया गया. वी.पी. सिंह इस बात पर भी सहमत हो गए कि पार्टी के प्रस्तावित कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर हों. पार्टी के संविधान को अंतिम रूप देने के लिए जपा अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में एक दूसरी समिति बनाई गई.

इन रियायतों से मतभेद दूर नहीं हुए. उलटे, विपक्षी नेताओं में और ज्यादा उलझन पैदा हो गई. जनता पार्टी में अंदर ही अंदर सुगबुगाहट चलती रही और लोकदल में पहले से ही मतभेद थे. बहुगुणा इस बात से नाराज थे कि वी.पी. सिंह ने समितियों के गठन के बारे में उनसे सलाह-मशविरा नहीं किया. कांग्रेस (स) की आशंकाओं को वी.पी. सिंह ने यह तर्क देते हुए दूर करने की कोशिश की कि नई पार्टी में योग्यता के आधार पर फैसले किए जाएंगे.

लेकिन इन सब बातों का सिर्फ कांग्रेस (स) पर ही नहीं बल्कि जनमोर्चा पर भी असर नहीं हुआ. जनमोर्चा संयोजक रामधन ने बंगलूर सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला किया क्योंकि वे भी विलय के विरोधी थे. मोर्चा के ज्यादातर सांसद रामधन के साथ थे क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी सीट नहीं गंवाना चाहता था. नई पार्टी में शामिल होने का मतलब है दलबदल कानून के तहत अपनी सीटें गंवाना.

बहुगुणा और उनके समर्थकों ने स्थिति को उस समय और भी जटिल बना दिया जब उन्होंने वी.पी. सिंह को शामिल किए बिना कम्युनिस्टों से गठबंधन की कोशिश की. बहुगुणा और उन्नीकृष्णन ने प्रमुख मार्क्सवादी नेताओं को अपने घर पर भोज के लिए आमंत्रित किया.

इन्हीं सब खेलों के कारण विपक्षी एकता अभी तक अधर में लटकी हुई थी. फिर भी वी.पी. सिंह विपक्षी एका कराने में कामयाब हो गए. पर इसे स्थायी रूप देने के लिए अभी काफी कुछ करना होगा.

—प्रभु चावला, बंगलूर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन आँखों से प्यार झलकता है

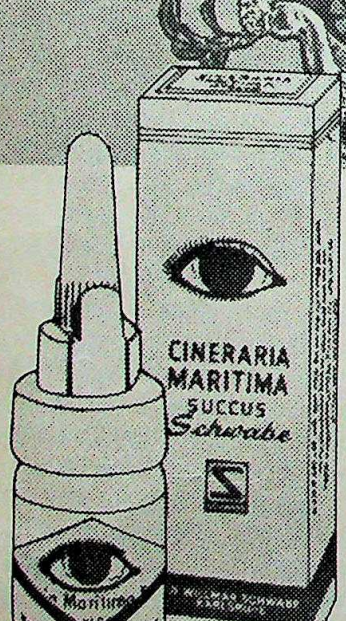

आँखें प्रकृति की देन हैं
इनको सुन्दर और सुरक्षित रखिए।

सिनेरेरिया श्वाबे

आँखों की सुरक्षा के लिए होम्योपैथिक फार्मूला

इसका निरन्तर प्रयोग आपकी आँखों को
साफ और स्वस्थ बनाये रखता है।

डा. विलमर श्वाबे द्वारा
पश्चिमी जर्मनी में
निर्मित तथा पैक किया गया।

SWAIN

SCHWABE **Schwabe**

सभी बड़े केमिस्टों से उपलब्ध

विश्वसनीय नेत्ररक्षक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

घर का सम्मोहन

बीर बहादुर की दखलंदाजी जारी

पिछले महीने की बात है. मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के साथ केंद्रीय संचारमंत्री बीर बहादुर सिंह अपने गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर गए थे. उनके साथ थे— इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथों मात खाने वाले पूर्व मंत्री सुनील शास्त्री और वर्तमान वन और शिक्षा राज्यमंत्री जगदंबिका पाल. अचानक जीप का डंडा टूट गया और तिवारी, पाल और शास्त्री गिर पड़े. लेकिन बीर बहादुर सिंह अपनी जगह बने रहे. शायद यह घटना उनके कैरियर से बहुत मेल खाती है.

आर.के. गुप्ता

बीर बहादुर सिंह अभी भी उ.प्र. में सत्ता के एक शक्तिशाली केंद्र, और तिवारी के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. और यह जताने के लिए वे दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी से भी बाज नहीं आते

लखनऊ में बीर बहादुर सिंहः मजबूत आधार

कोई भी अप्रत्याशित झटका हो, बीर बहादुर का संतुलन नहीं गड़बड़ाता. तीन महीने पहले उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्रीय संचारमंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. राज्य की राजनीति में उनकी दखल बरकरार है. केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वे दिल्ली के बजाय लखनऊ में ही ज्यादा पाए जाते हैं. संचार मंत्रालय भला चुनावी रूप से खास अहम राज्य उत्तर प्रदेश का कहां मुकाबला कर सकता है!

जब भी बीर बहादुर शहर में होते हैं तो माल एवेन्यू के उनके बंगले के बाहर दर्जनों कारों की कतार लगी होती है जिसमें तिवारी मंत्रिमंडल के सदस्यों की कारों की संख्या ही ज्यादा होती है. इधर तो हालत यह है कि वरिष्ठ अधिकारी भी उनसे मुलाकात करने आने लगे हैं. जाहिर है वे अभी भी राज्य में सत्ता के एक शक्तिशाली केंद्र और तिवारी के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. और यह जताने के लिए वे अपनी सीमा से बाहर भी चले जाते हैं. ममलन, तिवारी के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले बीर बहादुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान मंत्री रहे आधा दर्जन विधायकों को टेलीफोन किया और उन्हें सूचना दी कि उन्हें नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि उन्होंने ही मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दिलवाई है.

इन एहसानमंद मंत्रियों का यह धड़ा अब बीर बहादुर का वफादार है, जबकि उनके नेता तिवारी हैं. बीर बहादुर इस बात से साफ इनकार करते हैं कि वे तिवारी को किसी तरह परेशान करना चाहते हैं. 'इंडिया टुडे' को उन्होंने बताया, "जब भी कोई राजनैतिक अथवा सरकारी काम निबटाना होता है तभी मैं यहां आता हूं. मैंने बिना किसी काम के कभी राज्य का दौरा नहीं किया. और आखिरकार क्या यह मेरा गृह राज्य नहीं है?"

जाहिर है बीर बहादुर अपने गृह राज्य को ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने गृह जिले गोरखपुर को. हाल ही में उन्होंने पूर्वी जिलों की 'जानबूझकर' उपेक्षा पर खासा विवाद छेड़ दिया. तिवारी के नजदीकी माने जाने वाले एक मंत्री ने 10 सितंबर को लखनऊ में बीर बहादुर से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन इसके पहले कि मंत्री कुछ और कहते, बीर बहादुर मुलाकातियों के सामने ही उन पर बरस पड़े, "मेरे चुनाव क्षेत्र और मेरे जिले की उपेक्षा करने की आपकी हिम्मत कैसे पड़ी? मैं सब जानता हूं, आगे कोई भी ऐसा न कर पाए."

इस घटना के 10 दिन बाद तिवारी बीर बहादुर को अपने मंत्री की बेइज्जती के लिए आड़े हाथों लेने के बजाय उनके साथ गोरखपुर गए और उन्होंने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की. तिवारी के एक मंत्री ने कहा, "यह शख्स (बीर बहादुर) ऐसा घुटा हुआ खिलाड़ी है कि तिवारी सरीखे मंजे हुए नेता को भी कई मौकों पर इसके आगे झुक जाना पड़ता है. मुख्यमंत्री उन्हें नाराज करना नहीं चाहते."

उदासीन तरीके से काम करने के अपने रवैये के कारण तिवारी अपने समर्थकों के चहेते भी नहीं बन पा रहे. दूसरी ओर बीर बहादुर के दरबार में देर-देर तक गपबाजी चलती रहती है. हाल ही में एक ऐसे ही दौर के बाद उन्होंने घोषणा की, "हम जल्द ही फिर मिलेंगे. मैं 1 अक्तूबर और उसके बाद 3 अक्तूबर और फिर 6 अक्तूबर को आऊंगा." और सचमुच वे तीनों दिन राज्य में मौजूद थे. 6 अक्तूबर को वे विधान सभा में पहुंच गए जहां तिवारी पूरक मांगों की सूची प्रस्तुत कर रहे थे. बीर बहादुर ने विधायकों के रजिस्टर पर दस्तखत किए जो कि किसी केंद्रीय मंत्री के लिए कतई अजूबा करतब ही है.

यद्यपि प्रधानमंत्री ने हाल ही में उन्हें हिदायत दी है कि वे राज्य के मामलों में दखलंदाजी न करें. लेकिन लगता नहीं कि आलाकमान बीर बहादुर को अपने प्यारे राज्य और राज्यस्तरीय राजनीति से दूर रखने में कामयाब होगा. —दिलीप अवस्थी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

सभी तीर नाकाम

असंतुष्टों पर अंकुश नहीं

इंका आलाकमान ने मानो उनको भुला ही दिया है. सो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के लिए पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष पर काबू पाना दुश्वार होता जा रहा है. राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी का कोई भी जाना-पहचाना दांव इस बार कारगर होता नहीं दिखता. मंत्रिमंडल विस्तार, पार्टी पदों की पेशकश और सुलह की बातचीत— अर्जुन के सभी तीर नाकाम होते नजर आते हैं. राज्य भाजपा अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा कहते हैं, "अर्जुन सिंह का दूसरा मुख्यमंत्रित्वकाल किसी पिटी फिल्म को दुबारा प्रदर्शित करने सरीखा है."

पिछले महीने असंतुष्टों पर अंकुश लगाने के मकसद से अर्जुन सिंह ने मंत्रिमंडल में 10 लोग शामिल किए. इनमें दो तो उनके विरोधी खेमे के ही थे. लेकिन मुख्यमंत्री को हटाने की मांग में इससे भी कोई कमी नहीं आई. उलटे उनके आलोचक हाल ही में इंका में शामिल हुए श्यामाचरण शुक्ल के इर्द-गिर्द जमा होने लगे. दो बार मुख्यमंत्री रह चुके शुक्ल अर्जुन सिंह के कट्टर विरोधी हैं. एक दशक तक पार्टी के बाहर रहने के बावजूद उनका लोगों में, खासकर छत्तीसगढ़ के इलाके में, अच्छा-खासा असर है.

लेकिन अर्जुन सिंह समर्थक इस बात से खुश हैं कि आखिर आलाकमान ने नए मंत्रियों की सूची पर अपनी मुहर लगा ही दी. अर्जुन सिंह खुद कहते हैं, "वोराजी और सिंधियाजी द्वारा कोई नाम न सुझाए जाने के बावजूद मुझे मंत्रिमंडल विस्तार की इजाजत मिल गई." केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमंत्री मोतीलाल वोरा और केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया की असंतुष्ट जोड़ी अर्जुन सिंह पर हमले के लिए पहले कभी अपने दुश्मन रहे श्यामाचरण शुक्ल के कारवां में शामिल हो गई है.

शुक्ल की वापसी को बागियों की हार बताया जा रहा है. अभी तक अर्जुन सिंह उनकी वापसी में यह कहकर रोड़े अटकाते रहे कि कांग्रेस में दोनों बार हुए विभाजनों के दौरान शुक्ल पार्टी को मंझधार में छोड़कर चले गए थे. शुक्ल अब असंतुष्टों के अगुआ बन गए हैं. रायपुर और भोपाल में उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. भोपाल में तो एक नारा यह भी लगा: "नई चेतना, नई उमंग— मोती, माधव, श्यामा के संग".

लेकिन अर्जुन सिंह पार्टी नेतृत्व के रुख को लेकर ज्यादा चिंतित हैं. असंतुष्टों की राजीव तक पहुंच अब आसान हो गई है. अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल से निकाले गए जय-

कार्टून: अजीत नैनन

पाल सिंह कहते हैं, "आलाकमान हमारी शिकायतों को गंभीरता से लेता है."

लेकिन असंतोष फैलने की जिम्मेदारी कुछ हद तक अर्जुन सिंह पर भी है. वोरा की जगह मुख्यमंत्री बनने के बाद वे मद में चूर रहे. उन्होंने वोरा और सिंधिया से सीधे टकराव का रास्ता अपनाया. उनके समर्थकों को भी मंत्रिमंडल और सरकारी निगमों से बाहर कर दिया गया.

अब शुक्ल की वापसी और पार्टी में समीकरण बदलने से अर्जुन सिंह का रुख नाराज हो गया है. कार्यकर्ताओं को पटाने के लिए उन्होंने करीब 1,500 पार्टी पदाधिकारियों से हाल में बातचीत की अगस्त में उन्होंने कृष्णपाल सिंह सरीखे अपने जाने-माने विरोधियों को विभिन्न पार्टी समितियों में शामिल करके बागियों से सुलह करने की कोशिश भी की.

सारी कसरत बेकार साबित हुई. वजह यह कि असंतुष्टों को अर्जुन सिंह के इरादों पर शक है. पिछले महीने ही जब अर्जुन सिंह ने वोरा और सिंधिया से मंत्रिपद के अपने उम्मीदवारों की सूची देने को कहा तो दोनों ने इस एहसान को ठुकरा दिया. बताया जाता है कि सिंधिया ने कहा, "मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं मानो आप विपक्षी सरकार चला रहे हैं और मैं इसमें हरगिज भागीदार नहीं बनना चाहता."

लेकिन अर्जुन सिंह ने शुक्ल से जोड़तोड़ बिठाने की कोई कोशिश नहीं की. दोनों के बीच कलह इतनी पुरानी है कि उसे भुला पाना मुश्किल है. पिछले कुछ वर्षों से अर्जुन सिंह शुक्ल बंधुओं— श्यामाचरण और उनके भाई जनमोर्चा नेता विद्याचरण शुक्ल की छत्तीसगढ़ में पकड़ कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं. हाल ही के मंत्रिमंडल विस्तार में आधे मंत्री तो छत्तीसगढ़ इलाके से शामिल किए गए थे.

इसके जवाब में शुक्ल ने अर्जुन सिंह की मुखालफत का अभियान छेड़ दिया. उनका कहना था, "राज्य पार्टी में निहित स्वार्थों वाले उन लोगों की घुसपैठ हो गई है जिन्हें इंका की नीतियों में विश्वास नहीं है." लेकिन अर्जुन सिंह का कहना था कि कुछ लोग इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश में जुटे हैं मानो किसी खास शख्स के पास जादुई छड़ी है. इस का ताल्लुक शुक्ल को अर्जुन सिंह का विकल्प बताए जाने की कोशिशों से था. वोरा कहते हैं, "शुक्ल पर बरसना एकदम बचकानी हरकत है."

बयानों की जंग तेज होने से दोनों ओर का रुख भी सख्त होता जा रहा है. असंतुष्ट खेमा मुख्यमंत्री को हटाए जाने के सपने देखता है. उधर, अर्जुन सिंह की अकड़ भी कायम है मानो वे मसीहा हों. लेकिन प्रभामंडल के बजाय उनके सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

—नरेंद्र कुमार सिंह

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओडीसा

वादाखिलाफी से नाराज

मुख्यमंत्री पटनायक का अपने ही चुनाव क्षेत्र में विरोध

पिछले कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक को अपने गढ़ की दीवारें ढहती नजर आ रही हैं. एक तो पार्टी के भीतर बढ़ रहे असंतोष के कारण पार्टी में उनका आधार सिकुड़ गया है. दूसरे, कई घोटालों के रहस्योद्घाटनों में उनकी छवि मलिन हुई है. लेकिन अब जबकि उन्हें अपने ही चुनाव क्षेत्र— अथगढ़— में अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो लगता है कि उनका अंतिम मजबूत गढ़ भी ढह सकता है. समुद्रतटीय जिला कटक का यह क्षेत्र 1980 से लगातार उन्हें जिताता रहा है.

पिछले पखवाड़े खतरे की घंटी तब बजी जब पूरे अथगढ़ शहर में पटनायक के नाम 'जनता की खुली चिट्ठी' बांटी गई. 34 पेज की इस चिट्ठी में पटनायक के खोखले वादों का जिक्र किया गया था. एक स्थानीय युवा संगठन 'अथगढ़ युवा समाज' ने तीन माह से चल रहे अपने पटनायक विरोधी आंदोलन को तेज करने की भी धमकी दे दी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योगमंत्री निरंजन पटनायक को तुरंत वहां रवाना किया. उन्होंने वहां जाकर स्थानीय लोगों के लिए कुछ सहूलियतों की घोषणा कर माहौल को थोड़ा ठंडा किया. पटनायक की ओर से उन्होंने टीन कारखाना, तेल निकासी कारखाना और बिजली करघा लगाने का वादा किया. युवा समाज ने तीन महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित रखने की घोषणा की. चैन की सांस लेते हुए पटनायक ने कहा, "मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है. मैं उनके लिए जो कुछ कर रहा हूं उससे वहां के लोग खुश हैं."

लेकिन सचाई कुछ और ही है. पिछले छह महीने से अथगढ़ में चुनावी वादों पर अमल न किए जाने के विरोध में हुए आंदोलनों, हड़तालों और प्रदर्शनों में स्थानीय युवकों के साथ इंकाई कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं. चूंकि पटनायक अपने वादों को पूरा करने में नाकामी के लिए 'विख्यात' रहे हैं इसलिए ताजा वादों के भी वादाखिलाफी की फेहरिस्त में ही शामिल हो जाने की पूरी-पूरी संभावना है:

► 1981 में पटनायक ने राधादामोदरपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी थी. दो साल बाद उन्होंने इसका उद्घाटन किया. आज इस क्षेत्र के सभी 10 कारखाने बंद पड़े हैं.

► 1983 में अथगढ़ शहर में प्रतिदिन 2,500 लीटर दूध को ठंडा रखने की क्षमता वाला एक संयंत्र लगाया गया. उम्मीद थी कि 14 सहकारी संस्थाएं इसे दूध की आपूर्ति करेंगी और दूध ठंडा करवाएंगी. इन सहकारी संस्थाओं में से 13 के बोरिया-बिस्तर समेट लेने से अब संयंत्र में प्रतिदिन मात्र 150 लीटर दूध ही ठंडा रखा जाता है.

► 1984 के लोकसभा चुनावों के पहले शुरू की गई 16 लाख रुपए की लागत वाली तैलमल छोटी सिंचाई परियोजना को 1986-87 में पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी यह अधूरी ही है. दुखद तथ्य तो यह है कि बाढ़ राहत की रकम को भी इस परियोजना में लगा दिया गया.

पटनायक और उनकी सांसद पत्नी जयंती के अधूरे वादों के ये कुछ नमूने भर ही हैं. उनके संसदीय क्षेत्र में अथगढ़ भी आता है. उपरोक्त खुली चिट्ठी के अनुसार पटनायक ने 5 करोड़ रु. के उद्योग लगाने का वादा किया पर इस पर कुछ भी नहीं हुआ; उन्होंने बेरोजगारी को मिटा देने का वादा किया पर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 10,000 है; उन्होंने क्षेत्र की इंच-इंच जमीन को सिंचित कर देने का वादा किया पर ज्यादातर सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं.

पटनायक औद्योगीकरण के इतने लंबे-चौड़े वादे करने की बात से अब मुकरते हैं. वे ध्यान बंटाने के लिए कामयाबी वाले क्षेत्रों की तरफ इशारा करते हैं. वे अपने क्षेत्र के सभी गांवों में बिजली, पीने का पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने और पक्की सड़कें बनवाने की बातें करते हैं. उनका कहना है कि दरअसल उनका विरोध अथगढ़ शहर तक ही सीमित है.

उनके समर्थकों का दावा है कि अथगढ़ की आबादी मात्र 12,000 ही है पर इसे मध्यम दर्जे के शहरों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर रखा गया है और इसके समग्र विकास के लिए 1.24 करोड़ रुपए रखे गए हैं.

पटनायक; और (नीचे बाएं से) पटनायक विरोधी प्रदर्शन; अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजना; दूध ठंडा रखने का संयंत्र

आर.एल. पटनायक

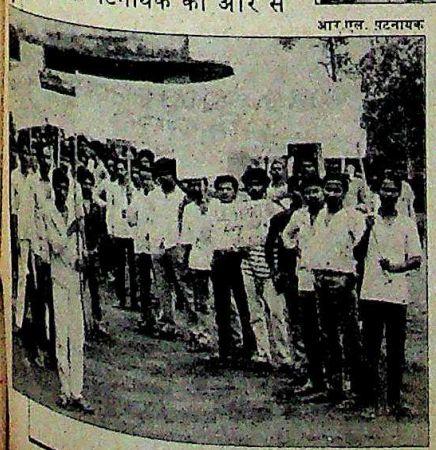

आर.एल. पटनायक

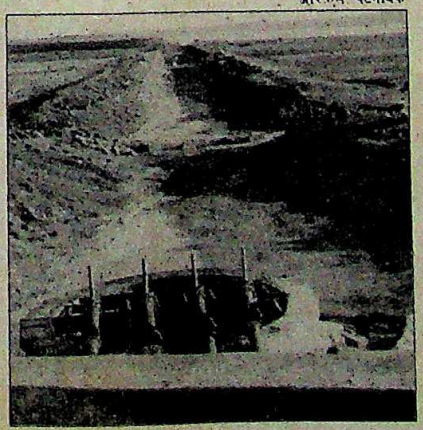

इस्टर्न प्रेस एजेंसी

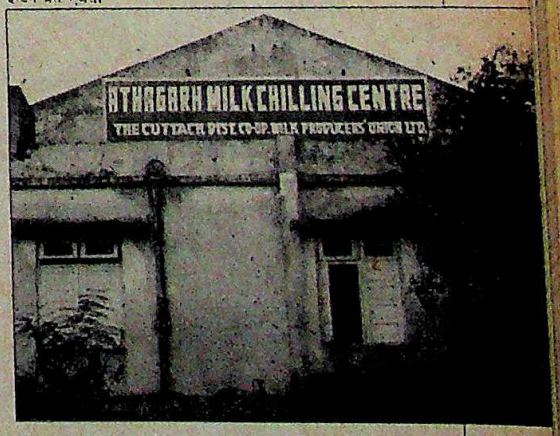

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पटनायक समर्थक कहते हैं कि क्षेत्र में एक ग्रामीण स्टेडियम, एक कोल्ड स्टोरेज, एक कपड़ा मिल, मवेशियों का चारा बनाने वाला एक कारखाना और एक चीनी मिल स्थापित की गई है. इसके अलावा सभी गांवों में स्कूल भी बने हैं.

लेकिन इंकाई असंतुष्टों का एक ताकतवर गुट इस क्षेत्र की दूसरी ही तस्वीर खींचता है. उनका मानना है कि सारे फायदे मुख्यमंत्री के करीबी मुट्ठीभर लोगों की झोली में ही पड़े हैं. पटनायक विरोधी इस आंदोलन के अगुआ हैं इंकाई विधायक रसानंद साहू. उन्होंने ही 1980 में मुख्यमंत्री के लिए अथगढ़ की सीट खाली की थी.

असंतुष्टों के हर आरोप का पटनायक के पास टका-सा जवाब है. वे पूछते हैं, "यदि लोग नाखुश हैं तो इतने भारी बहुमत से वे हमें क्यों जिताते हैं?"

उनकी बार-बार जीत की एक वजह तो पैसे की ताकत भी हो सकती है. ताकतवर ओड़िया दैनिक 'समाज' के संपादक राधानाथ रथ कहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक दो दिन पहले जयंती की जीत सुनिश्चित कराने के लिए 1.6 लाख रुपए बांटे गए.

इससे साफ है कि अथगढ़ की राजनैतिक आबोहवा दूषित हो गई है. पटनायक के लिए इससे भी चिंताजनक बात तो यह है कि लोगों के तेवर तीखे हो रहे हैं और वे अब अपना हिस्सा मांगने पर उतारू दिखते हैं. इस तूफान को थामने के लिए कुछ और सहूलियतों के वायदे करने की पटनायक की रणनीति उनके के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है.

—फरजंद अहमद, अथगढ़ में

बिहार

सख्ती का स्वांग

आजाद का कुर्सी बचाओ प्रयोग

गांधी जयंती एक ऐसा दिन है जब ज्यादातर कांग्रेसी पूरे शबाब पर होते हैं. वे लच्छेदार भाषण झाड़ते हैं, सदाचार की शपथ लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि दरअसल वे ही महात्मा गांधी के सच्चे वारिस हैं. बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने भी इस गांधी जयंती को अनेक वादे किए. लेकिन इस बार उनका भाषण काफी सख्त था.

रेडियो पर प्रसारित इस भाषण में दुहरा संदेश था. राज्य की जनता को बताया गया कि मुख्यमंत्री के पास उनकी अनंत समस्याओं से निबटने के लिए सचमुच राजनैतिक संकल्प मौजूद है. ज्यादा महत्वपूर्ण तो इंका असंतुष्टों के नाम वह तीखा संदेश था जिसमें जताया गया कि कम-से-कम अगले आम चुनावों तक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने से रही.

कोई भी डांवाडोल नेता आजाद सरीखे वादे करने की जुर्रत नहीं कर पाता. सबसे महत्वपूर्ण वायदा अगले तीन महीनों में किए जाने वाले भूमि सुधारों का था.

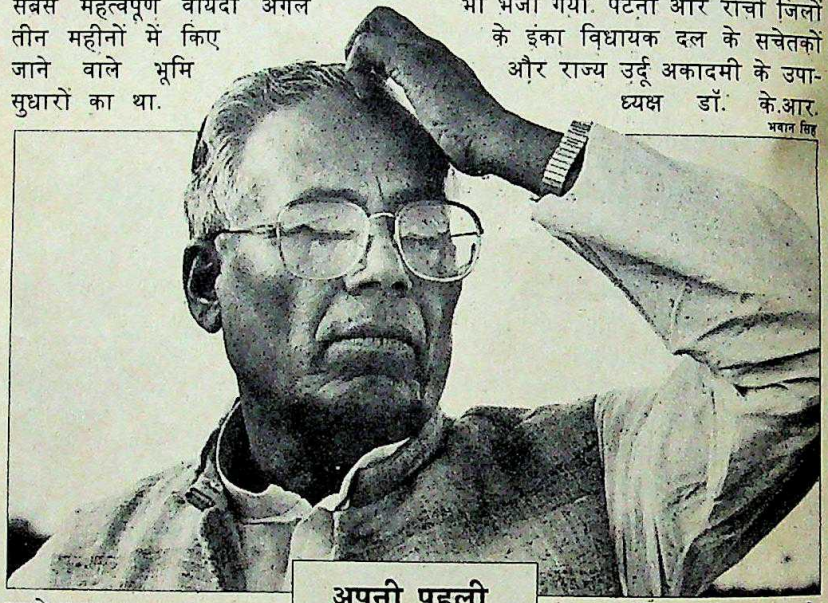

भवान सिंह

अपनी पहली बड़ी नीतिगत घोषणा में आजाद ने महत्वपूर्ण भूमि सुधारों का वायदा किया है

इसके तहत ताकतवर भूस्वामियों से एक लाख एकड़ फालतू जमीन अधिग्रहीत करके कमजोर तबको में बांटी जाएगी. इसके अलावा आबंटियों को 10 करोड़ रु. की आर्थिक मदद भी दी जाएगी. आजाद गरजदार आवाज में बोले, "मूल बात आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय की है." आजाद ने मार्च 1989 तक 25,000 सिंचाई नलकूप, 25,864 हैंडपंप, 17,187 पानी के कुएं और गांवों में 8,200 किमी लंबी जोड़ सड़कों के निर्माण के वायदे भी किए.

भूमि सुधार योजना के जरिये आजाद एक तीर से दो शिकार करने की उम्मीद कर रहे हैं. पहले तो उनका मकसद देहाती गरीबों का विश्वास जीतना है. दूसरे, असंतुष्टों पर हल्ला बोलना है. ज्यादातर असंतुष्ट ताकतवर भूपति हैं.

पार्टी में आजाद के विरोधियों का कहना है कि यह कड़ा रवैया महज लाज बचाने के लिए है क्योंकि असंतुष्टों की गतिविधियां काबू से बाहर होती जा रही हैं. पिछले पखवाड़े करीब 100 विधायकों ने आजाद को हटाने की रणनीति गढ़ने के लिए बैठक की थी. असंतुष्टों का दावा है कि आजाद के खिलाफ प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन पर राज्य के 324 में से 125 से ज्यादा विधायकों ने दस्तखत किए हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री रामजयपाल सिंह यादव की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली भी भेजा गया. पटना और रांची जिलों के इंका विधायक दल के सचेतकों और राज्य उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष डॉ. के.आर. साबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. पूर्व मंत्री और मुसलमानों पर खासी पकड़ रखने वाले साबा ने आज़ाद पर उर्दू की जान-बूझकर उपेक्षा करने का आरोप लगाया.

इन घटनाओं से चिंतित राजीव गांधी ने सांसद जगन्नाथ मिश्र और केंद्रीय श्रममंत्री बिंदेश्वरी दुबे से मशविरा किया. पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली आए असंतुष्टों को मुलाकात का वक्त नहीं दिया. इसके बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री शीला दीक्षित और इंका महासमिति में बिहार के मामलों के प्रभारी महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस ने बागियों को बताया कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं. इसके बाद राजीव ने अलग से मुख्यमत्री भागवत झा आजाद से 45 मिनट तक बातचीत की. इस मुलाकात के बाद आजाद ने 'इंडिया टुडे' को बताया, "मैं असंतुष्टों के खेल में नहीं फंसना चाहता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Casual
The Oxford Collection.
On the move. Swift and sober, soft and rugged. Designs to suit the occasion. Sedate blacks, to rangy browns. And yes, the bold reds. Match your moods.
"Now go ..... build yourself a great shirt."
DESIGNER FABRICS FOR SHIRTS BY
oxford
Ask for Oxford.

TVs / Radios / 2-in-1s / Calculators / Projectors / Digital Watches

KELTRON

RELYTRONICS

No better guarantee

रिलायट्रॉनिक्स.

अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके साथ विश्वसनीयता जुड़ी है.

वैसे हमारे लिए विश्वसनीयता महज एक शब्द ही नहीं बल्कि पिछले बीस सालों में विस्तृत श्रृंखला के औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों के निर्माण में हासिल किये गये हमारे अनुभव और तकनीकी कुशलता का प्रतीक है.

इन उत्पादनों में टी.वी, रेडियो, टू-इन-वन, कैलकुलेटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के अलावा संचार, देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किये जानेवाले इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम भी शामिल हैं. और तो और, हम इन उत्पादनों में इस्तेमाल होनेवाले कलपुर्जे, जैसे कैपेसिटर्स, डायोड्स, रेसिस्टर्स, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स वगैरह भी बनाते हैं.

यही नहीं, कई नामी कंपनियां भी अपने उत्पादनों के निर्माण के लिए हमारे ये कलपुर्जे खरीदती हैं.

केल्ट्रॉन रिलायट्रॉनिक्स : इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वसनीयता के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं.

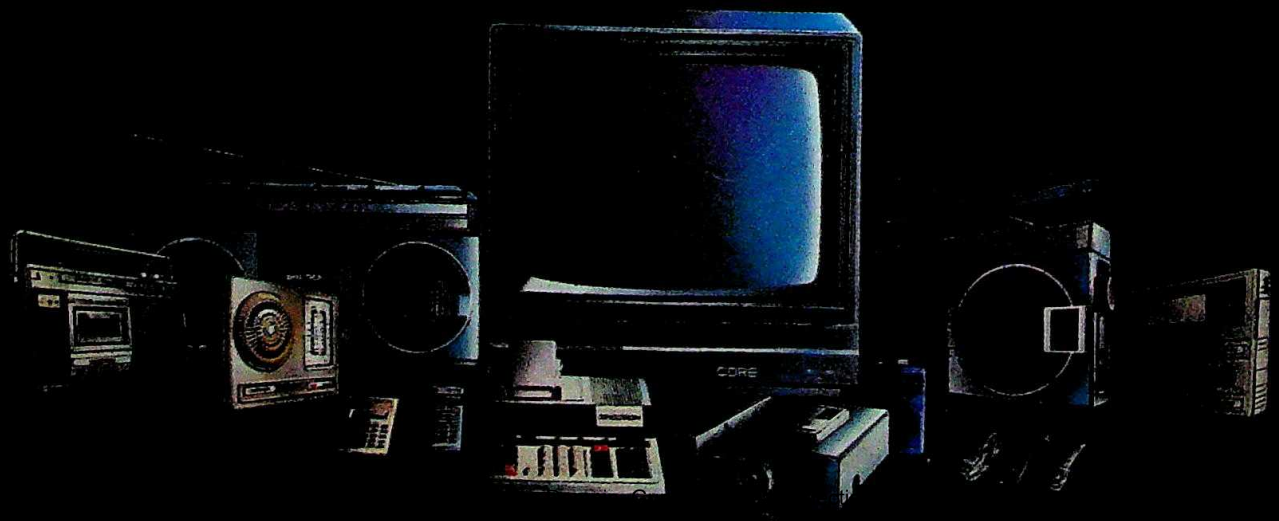

केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड : कॉर्पोरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट (कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स), शास्थमंगलम, त्रिवेन्द्रम ६९५ ०१०. फोन ६९१०६ शाखा ७

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आलीशान, आकर्षक, फ़ैशनेबल... बेहतरीन विमल सूटिंग की कहानी...रवि शास्त्री की जुबानी.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्दियों के लिए ☐ विमलकी ☐ पेशकश

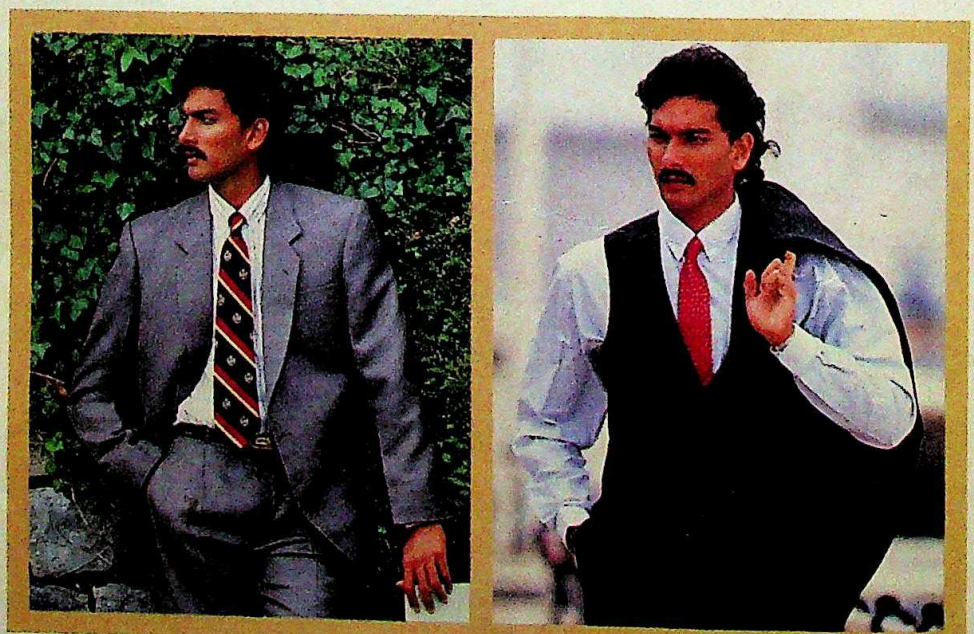

विजेताओं की शान

VIMAL
A RELIANCE PRODUCT

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्योंकि मुझे इससे भी ज्यादा कई अहम काम करने हैं. शुरू से ही मैंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है. आइंदा भी मैं ऐसा ही करता रहूंगा."

लेकिन आजाद को आलाकमान के खुले समर्थन और एकता के दावों के बावजूद बहुत से नेता मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा छोड़ नहीं पाए. बिहार की गद्दी के दावेदारों में इस समय ये लोग हैं:

विदेश्वरी दुबे: उन्हें हालांकि आजाद के लिए जगह खाली करने की खातिर केंद्र ले आया गया था पर वे अपने गृह राज्य में लौटना पसंद करेंगे. पिछले पखवाड़े नई दिल्ली में उनके समर्थकों से इस बिना पर तुरंत पटना पहुंचने को कहा गया कि 'किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है और दुबे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण' कर सकते हैं.

सीताराम केसरी: प्रत्यक्ष रूप में वे हालांकि मुख्यमंत्री आजाद का समर्थन कर रहे हैं लेकिन इंका के चतुर कोषाध्यक्ष ने अपनी छवि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और कमजोर तबकों के नेता के रूप में बनानी शुरू कर दी है.

जगन्नाथ मिश्र: शक्तिशाली पूर्व मुख्यमंत्री ने फिलहाल सुलह का रुख अपना रखा है. लेकिन मौका मिलने पर वे अब भी आजाद पर हमला बोलने से नहीं चूकते, "जनता का आजाद से मोहभंग हो गया है क्योंकि वे सरकार और पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे हैं."

तारिक अनवर: इस सांसद और प्रदेश इंका अध्यक्ष ने आजाद से मतभेद होने की वजह से दो महीने पहले राज्य की 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन सावधानी बरतते हुए वे कहते हैं, "आजाद का विरोध करने की कोई भी कोशिश आलाकमान का विरोध मानी जाएगी... असंतुष्टों की कुछ शिकायत सही भी हो सकती है."

इसके अलावा एल.पी. साही, रामजयपाल सिंह यादव और कृष्णा साही भी भावी मुख्यमंत्री की कतार में हैं. जाहिर है कि आजाद को कड़े विरोध का सामना है. शायद इस वजह से भी उन्हें अपनी पहली बड़ी नीतिगत घोषणा करने में आठ महीने लग गए.

लेकिन लोगों को जन्नत के ख्वाब दिखाकर आजाद ने शायद अपनी परेशानियां बढ़ाई ही हैं. अगर वे अपने आधे वादे भी पूरे कर पाएं तो कामयाब माने जाएंगे. पर अगर वे नाकाम रहे तो असंतुष्टों की ख्वाहिश ही पूरी होगी. —फरजंद अहमद

केरल

दांव उलटा पड़ा

शिक्षामंत्री नए झमेले में

देश में सबसे ज्यादा साक्षरों वाले इस राज्य के लिए शिक्षा बेहद नाजुक मसलों में से एक है. ऐसे में शिक्षामंत्री के. चंद्रशेखरन विवादों के दुष्चक्र में फंस जाते हों तो अचंभे की बात नहीं.

पिछले पखवाड़े वे उस वक्त मुसीबत में फंस गए जब उन्होंने शिक्षा सचिव बाबू पॉल से मशविरा किए बिना त्रिवेंद्रम के प्रतिष्ठित होली एंजल्स कान्वेंट हाईस्कूल की मान्यता रद्द कर दी. 100 साल पुरानी इस शाला को कार-मेलाइट समुदाय की सिस्टर्स चलाती हैं. सेकंडरी स्कूल परीक्षा की प्राविण्य सूची में इस शाला के जितने विद्यार्थियों ने स्थान पाए हैं उतने तो राज्य की सभी शालाओं के विद्यार्थियों को मिलाकर भी प्राप्त नहीं हुए.

मामले की शुरुआत पिछले साल जून में हुई. शाला के प्रबंधन ने 15 अध्यापकों को यह कहते हुए बरखास्त कर दिया कि "उनके पास नियत योग्यता नहीं है और वे सक्षम भी नहीं हैं." बरखास्त अध्यापकों में से सात तुरतफुरत शक्तिशाली मार्क्सवादी श्रमिक संगठन सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) में शामिल हो गए और आंदोलन शुरू कर दिया. इस बीच होली एंजल्स ने पुलिस संरक्षण का अदालती आदेश हासिल कर लिया. उधर अध्यापकों ने बरखास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली और शिक्षामंत्री से मुलाकात कर न्याय की मांग की. वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने उनका मामला अपने हाथ में ले लिया. लेकिन शाला के प्रबंधक सरकारी कार्रवाई के खिलाफ अदालत से स्थगनादेश पाने में सफल हो गए.

सीटू को खुश करने की जल्दबाजी में सरकार में जनता पार्टी के सदस्य चंद्रशेखरन ने तथ्यों की जांच-पड़ताल की जहमत उठाए बगैर होली एंजल्स कान्वेंट की मान्यता रद्द कर दी. वे भूल गए कि होली एंजल्स को सरकारी अनुदान नहीं मिलता.

जैसा कि अंदेशा था, मंत्री की इस कार्रवाई से ईसाई पादरी भड़क उठे. भारतीय केथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष ऑर्क बिशप बेंडिट मार ग्रेगोरियस ने आरोप लगाया, "शैक्षणिक जगत से निजी क्षेत्र को बाहर कर देने की सरकार की यह सुनियोजित कोशिश है." विवाद तूल पकड़ा तो मार्क्सवादियों के हाथ-पांव फूल गए. सरकार ने चंद्रशेखरन से आदेश वापस लेने को कहा. वे बेचारे क्या करते, उन्हें अपना आदेश 'अस्थायी तौर पर निरस्त' कर देना पड़ा.

कुछ ही अरसे बाद चंद्रशेखरन एक और झमेले में उलझ गए. कालीकट विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद ने अपने अध्यापकों

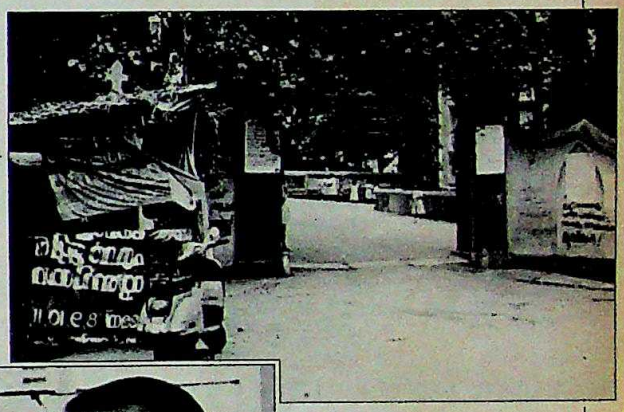

होली एंजल्स कान्वेंट; और (बाएं) चंद्रशेखरन

को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने का फैसला किया. चंद्रशेखरन का कहना था कि यह फैसला अवैध है क्योंकि इस मसले पर नए कुलपति टी.आर. रवींद्रन ने उनसे सलाह नहीं ली लेकिन असली वजह कुछ और है. शिक्षामंत्री को शायद अंदेशा है कि इससे दूसरे विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी वेतनमान सुधारने की मांग करेंगे. मांगें पूरी करनी पड़ीं तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा. राज्य के योजनाविदों ने वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए शालाओं और महाविद्यालयों की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पहले ही उनके पास भेज रखे हैं. चंद्रशेखरन विवादों की जितनी तगड़ी गिरफ्त में हैं उसे देख यह नहीं लगता कि वे किसी नए विवाद को न्यौता देंगे. —श्रीधर पिल्लै

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

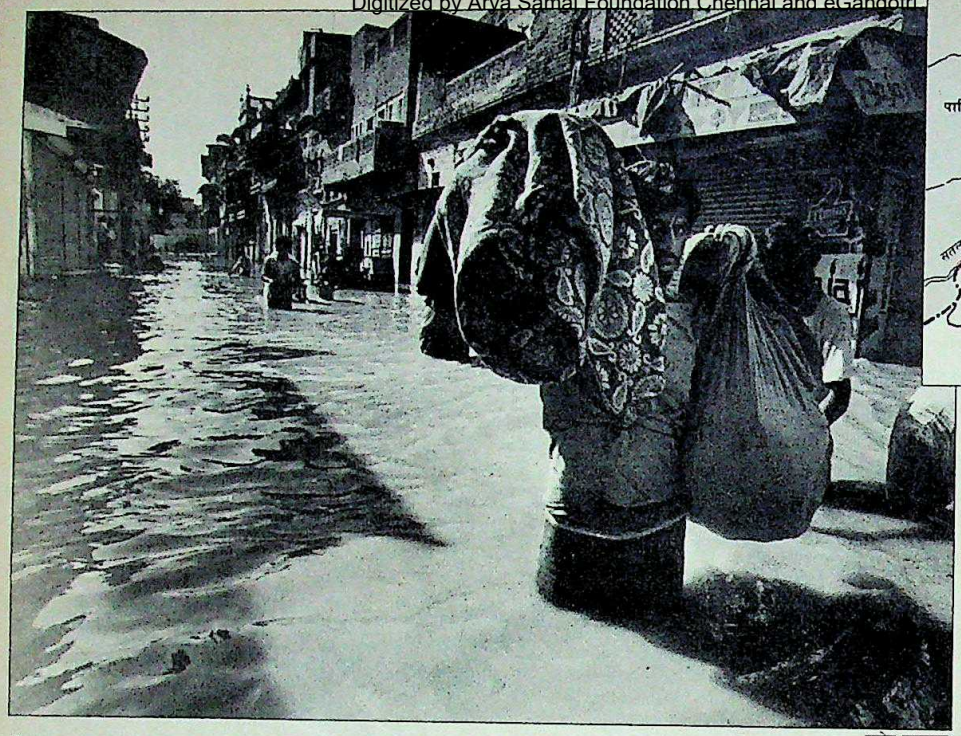

प्रमोद पुष्करणा

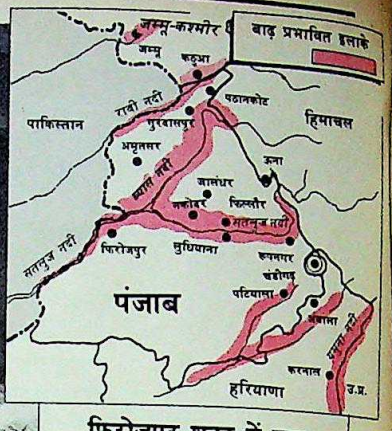

फिरोजपुर शहर में बाढ़ का पानी: बरबादी

पंजाब

अप्रत्याशित विपत्ति

बाढ़ से हुई भयानक तबाही

आतंकवाद की मार झेल रहे पंजाब की मुश्किलें पिछले पखवाड़े और बढ़ गईं. भाखड़ा और पोंग बांधों से विशाल मात्रा में छोड़े गए पानी ने जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में भयानक तबाही मचा दी. 1500 लोग तो इस बाढ़ में जान गंवा ही बैठे, खरीफ की शानदार फसल का 75 से 80 फीसदी भाग जलमग्न होकर बिलकुल बरबाद हो गया.

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पर तुरंत आरोप लगने लगा कि उसने बिना पर्याप्त चेतावनी दिए अचानक इतना पानी छोड़ दिया कि ब्यास और सतलुज नदियां पंजाब के लिए कहर बन गईं. अगर यह पानी ठहर-ठहरकर छोड़ा जाता तो न तो इतनी मौतें होतीं और न ही फसल की इतनी जबरदस्त बरबादी होती.

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल बी.एन. कुमार कहते हैं कि वे इस मामले में बांध के अधिकारियों की कार्रवाइयों की जांच का स्वागत करेंगे. लेकिन वे यह भी कहते हैं कि पानी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि भाखड़ा बांध को खतरा पैदा हो गया था. उनका कहना है कि ठहर-ठहरकर पानी छोड़ना खतरनाक मौसम और 22 से 26 सितंबर के बीच बादल फटने की वारदातों के कारण संभव नहीं था. कुमार कहते हैं कि ऐसी अचानक बाढ़ "हजार वर्षों में एकाध बार ही आती है."

कुमार मौसम विभाग को दोषी ठहराते हैं कि इसने भारी बारिश की चेतावनी पहले नहीं दी. वे कहते हैं कि अगर पहले चेतावनी दी गई होती तो बाढ़ को काबू में किया जा सकता था. तब भाखड़ा और पोंग बांध के प्रबंधक पानी का स्तर पहले से ही नीचा रखते ताकि अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने से बाढ़ का खतरा नहीं पैदा होता. कुमार बताते हैं कि जब बारिश शुरू हुई थी उसके पहले से ही दोनों जलाशयों में भरपूर पानी भरा हुआ था.

लगता है कि मौसम विभाग ने गड़बड़ी की. उसने पूरे सितंबर महीने के लिए केवल 121 मिमी वर्षा की भविष्यवाणी की थी. स्थिति मौसम विभाग के महानिदेशक की एक विज्ञप्ति के कारण भी विकट हो गई, जिसमें कहा गया था कि सितंबर में 18 फीसदी कम वर्षा होने की संभावना है. इसलिए दोनों बांधों के अधिकारी केवल 100 मिमी वर्षा की उम्मीद कर रहे थे. इसलिए भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर अपनी अधिकतम क्षमता 1400 फीट के आसपास रखा गया था.

लेकिन केवल चार दिनों में — 23 से 26 सितंबर के बीच— भाखड़ा क्षेत्र में 640 मिमी और पोंग क्षेत्र में 644 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई. भाखड़ा में सिर्फ 45 मिनट में 85 मिमी वर्षा हुई. मौसम विभाग ने पूरे महीने के लिए यह औसत बताया था.

राज्य के सिंचाई सचिव रजिंदर सिंह के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य की तीनों बड़ी नदियां— रावी, ब्यास और सतलुज— एक ही साथ उफन पड़ीं. 1978 में जबकि रावी के कारण और 1955 में सतलुज के कारण बाढ़ आई थी, इस बार तीनों नदियों ने तबाही मचा दी.

दोनों बांधों से छोड़े गए पानी ने कितनी तबाही मचाई होगी इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 से 28 सितंबर के बीच भाखड़ा बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. पूरे अगस्त महीने में केवल ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. इसी तरह उन चार दिनों में पोंग बांध से सात लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जबकि पूरे अगस्त में केवल डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था.

साफ है कि लोगों को चेतावनी देने का पर्याप्त समय नहीं था. जब तक लोगों को खतरे का पता चलता तब तक खतरा धमक पड़ा. उन्हें अपना घर, अपनी फसल और अपनी जान तक बचाने का मौका नहीं मिल पाया. इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया. 1955 और 1978 की बाढ़ देख चुके बूढ़े-बुजुर्गों को उम्मीद थी कि इस बार की बाढ़ भी झेल लेंगे. लेकिन उन्हें आसन्न संकट की गंभीरता का पता नहीं था. दोनों जलाशयों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SONATA NEWS

Bangalore • September 1988

Language publishing to soon hit new heights

Prakashak, the 8-language software solution for DTP, launched

Until now, desktop publishing was relevant to mostly English language publishing.

Prakashak, Sonata's new,8-language software solution for DTP, now offers DTP users an opportunity to cash in on the large language publishing market.

With **Prakashak,** not only can DTP users profit from their ability to offer language publishing on a job-basis—small/medium publishers can now change to language DTP for faster, better results and more productivity!

'Prakashak' interfaces with 'Ventura Publisher', the world's most popular page-layout software.

The 'Prakashak' potential

Whether it's book, magazine or newspaper publishing, every small or medium size publisher can avail of **Prakashak's** DTP capabilities for publishing in Bengali, Devanagari – Hindi/Marathi, Gujarati, Kannada, Malayalam, Tamil or Telugu.

Offers desktop publishing in Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali and Gujarati. Will eventually offer in Oriya and Assamese too.

An integrated solution

Never before has a regional language DTP software offered such simplicity in use and so many versatile features in one integrated package.

Prakashak combines the features of MultiWord, a leading multi-lingual wordprocessor, with the speed and the power of the largest selling page composition software in the world—Ventura Publisher. What's more, with **Prakashak** you get professional quality display and printer fonts. These fonts are under licence from ITR – the only recognised type design institute in India.

How 'Prakashak' works

Text is entered in the bi-lingual text editor in an Indian language, and is edited and saved as a Ventura format file. Another option in the editor allows down-loading language fonts to the laser printer. The language display fonts are added to the Ventura Publisher font table, and edited text (in regional and/or English) directly loaded into it, with illustrations if any. The text is then page-composed and finally printed out on any popular laser printer using **Prakashak's** printer fonts.

Prakashak works on a PC, with a hard disk and a CGA or HGA card.

Regd. trademarks
Ventura Publisher of Xerox.PostScript of Adobe.
Prakashak, ResQ, IBIS, Super Shop, MultiWord of Sonata.

prakashak
from Sonata

One of India's leading software houses, Sonata is a division of Indian Organic Chemicals Limited – and a symbol of quality software solutions. Many of Sonata's products, including ResQ, WordLord Super, IBIS and MultiWord are market leaders today. In addition to software solutions, Sonata offers quality hardware for your DTP needs, with full pre-and post-purchase support.

Ask for a demonstration today. Contact:

SONATA

Sista's-1536/88

Software Division of Indian Organic Chemicals Limited.

1/4, I Floor,APS Trust Building,Bull Temple Road, N R Colony, Basavanagudi,**Bangalore** 560 019 Tel: 620863/622359
Telex: 0845-8843 SONA IN

208, T V Industrial Area, S K Ahire Marg, Worli **Bombay** 400 025
Tel: 4948336/4921931 Telex: 011-73951 CHIP IN

Gagan Deep, 12, Rajendra Place **New Delhi** 110 008 Tel: 5717432/5718749/5718309/5720476 Telex: 031-77003 IOCL IN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से प्रवाहित 10 फीट ऊंचे पानी के रेले ने चंद घंटों में ही गांव के गांव डूबो दिए. सड़कें और पुल डूब गए. पूरी संचार व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई. राजधानी चंडीगढ़ और बाढ़ पीड़ित जिलों के बीच संपर्क का माध्यम सिर्फ वायरलेस रह गया था और वहां हेलिकॉप्टरों या सेना की नौकाओं के जरिये ही पहुंचा जा सकता था.

पंजाब के किसान शानदार खरीफ फसल की खुशियां मना ही रहे थे कि चार दिनों की बारिश ने उनकी तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया. अब तक की सबसे भयावह बाढ़ के कारण पहले से ही संकटग्रस्त अनाज भंडार इस तबाही से और संकट में पड़ गया. विडंबना यह है कि पिछले तीन साल के सूखे और अनियमित बारिश के बाद इस बार बारिश अच्छी हुई थी. प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इस बाढ़ से अकेले कृषि क्षेत्र को 300 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. फसल तो बरबाद हुई ही, 1500 लोगों के मारे जाने के अलावा 500 लोगों के लापता होने की भी खबर है. लेकिन सरकारी आंकड़े हमेशा की तरह अधूरी कहानी कह रहे हैं— 607 लोग मारे गए और 92 लापता हैं. पंजाब के 9000 में से 12,989 गांव बाढ से प्रभावित हुए और इनमें से 2,500 पूरी तरह डूब गए. 34 लाख लोगों पर इस बाढ़ का असर पड़ा.

लगता था कि पंजाब उन्हीं नदियों की धाराओं में डूब जाएगा जिनके नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा है. और उधर लोग जबकि इस संकट से जूझ रहे थे, कृषिमंत्री भजनलाल ने इस बाढ़ को 'गुप्त वरदान' घोषित कर दिया. उनका तर्क था कि इससे पंजाब के भूमिगत जल का स्तर ऊपर होगा. भजनलाल की यह अविश्वसनीय आशावादिता तो अपनी जगह, राज्य के किसान तो फिलहाल अपने नुकसानों का जायजा ले रहे हैं. राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय भी उन्हें बहुत भरोसा दिलाते हुए नहीं दिख रहे हैं, "इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की हम भरपाई नहीं कर सकते. हम सिर्फ प्रभावित लोगों को राहत भर मुहैया करा सकते हैं."

—विपुल मुद्गल

बात पते की: कलमची

और भी हैं महारती

पिछले पखवाड़े भारतीय खिलाड़ी एक और ओलंपिक से खाली हाथ लौट आए. पदकों की जरूरत भी क्या है, बड़े-बड़े पदों के मालिक इनका हर्जाना पूरा कर ही लेते हैं. खेलों के बाद हांगकांग या दुबई में अधिकारियों के होने वाले 'ओलंपिक' की बदौलत कई 'ट्रॉफियां' उनके घरों की शोभा बढ़ाने लगती हैं.

अब जबकि यह सब खत्म हो गया है, मौका है कि खेल-खराबी की खोज-खबर ली जाए. क्या पी.टी. उषा अपनी दुखती नब्ज से उबर पाएंगी? क्या भारतीय मुक्केबाज अपने मुक्कों में और ताकत भर सकेंगे? दरअसल, मसला तो एकदम साफ है. हर कोई अपने खेल की डींगें हांकता है. हकीकत यह है कि बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मौका मिले तो बेहतर खेल दिखा सकते हैं. कुछ बानगियां:

100 मीटर (पुरुष): *राजीव गांधी का कोई भी निजी सुरक्षा गार्ड, जिसे प्रधानमंत्री की भागती कार के साथ-साथ दौड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है.*

100 मीटर (महिलाएं): मणिशंकर अय्यर, जो हमेशा ही महिलाओं की संगत में बेहतर काम कर दिखाते हैं.

400 मीटर रिले: अफसरशाह, जो 'बला' दूसरे के मत्थे टालने में इतने माहिर हैं कि उनके लिए 'बैटन' की क्या बिसात.

400 मीटर बाधा दौड़: विपक्ष के एड मोजेस यानी चंद्रशेखर. बाधाएं पेश करने में जिनका अटूट रिकार्ड है.

जिम्नास्टिक्स: हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनकी राजनैतिक कलाबाजियां रूसी जिम्नास्ट डेनिएला सिलिवास के लिए भी रश्क का कारण हो सकती हैं.

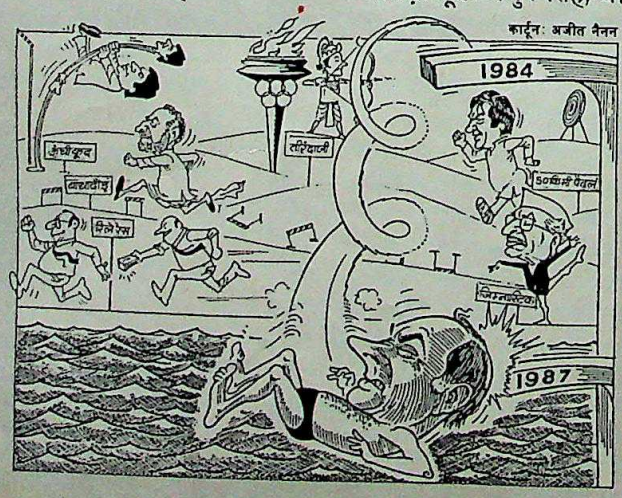

गोताखोरी: राजीव गांधी, जिनकी लोकप्रियता ने जो डुबकी मारी है उसका शायद लुगानिस ही मुकाबला कर सकें.

कुश्ती: कोई भी भारतीय यात्री जिसे सुबह सवेरे बस पकड़ने या ट्रेन पर चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की करनी पड़ती है.

50 किमी पैदल चाल: सुनील दत्त, जिन्हें पदयात्राओं में महारत हासिल है.

पोल वॉल्ट: अजिताभ बच्चन, बंबई के एक उपनगर से स्विट्जरलैंड तक जिनकी कुदान निश्चित रूप से स्वर्णपदक दिलाने के लिए काफी है.

बैडमिंटन: शिवशंकर, जो शटल कॉक की तरह महकमों के फेरबदल के पूर अभ्यस्त हो गए हैं.

मैराथन (पुरुष): सुरेश कालमाडी (इन्हें मोटा रोजा भी कहते हैं), जिनकी 'आजादी की दौड़ें' और पुणे मैराथन दर्शाते हैं कि वे कितनी भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, खासकर तब जब राजीव भी शामिल हों.

मैराथन (महिलाएं): रेखा, जो अपनी हमपेशाओं से काफी समय से आगे हैं और कोई भी उनके मुकाबले टिक नहीं पाती.

तिकड़ी कूद: अर्जुन सिंह, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर छलांग लगाने के बाद कैबिनेट मंत्री और फिर मुख्यमंत्री पद की ओर कूदकर विश्व रिकार्ड कायम कर चुके हैं.

निशानेबाजी: बोफोर्स तोप से गुप्त तौर पर लैस भारत की सरकारी टीम बाजी मार सकती है, बशर्ते इनाम खासा बड़ा हो.

मुक्केबाजी: लोकसभा के सदस्य, जिनका इस कला में कोई सानी नहीं.

मुख्य प्रशिक्षक: सतीश शर्मा, जिनकी सलाह कई पदक दिला सकती है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पॉलिसीधारकों के लिए बोनस अब नई ऊंचाईयां छू रहा है.

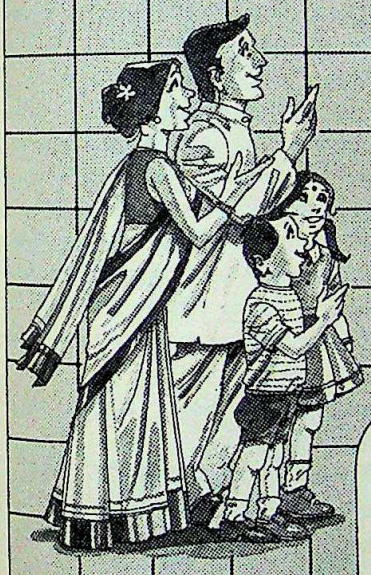

1988

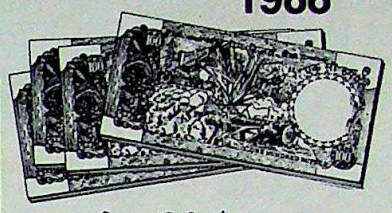

आजीवन पॉलिसियाँ
★ रु. 77.50
बन्दोबस्ती पॉलिसियाँ
☆ रु. 62.00

1987

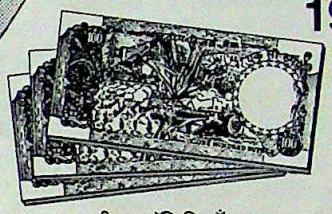

आजीवन पॉलिसियाँ
★ रु. 72.50
बन्दोबस्ती पॉलिसियाँ
☆ रु. 58.00

1986

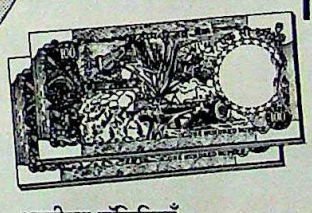

आजीवन पॉलिसियाँ
★ रु. 65.00
बन्दोबस्ती पॉलिसियाँ
☆ रु. 52.00

1985

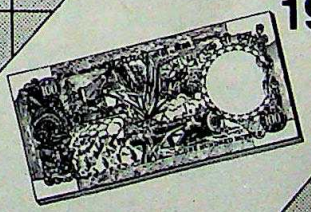

आजीवन पॉलिसियाँ
★ रु. 55.00
बन्दोबस्ती पॉलिसियाँ
☆ रु. 44.00

★☆ प्रति रु. 1000 बीमित राशि प्रति वर्ष.

बोनस की यह वृद्धि, हाल ही में दी गई अच्छी ख़ासी बढ़त के अतिरिक्त है. पिछले 5 वर्षों में बोनस में 82% की वृद्धि हुई है.

जीवन बीमा निगम लगातार इस कोशिश में है कि वह उपलब्ध राशि का सही सुचारु प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, ख़र्चों में कमी तथा हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाए जिससे पॉलिसीधारकों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा दिया जा सके.

31 मार्च 1988 को किए गए मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बोनस की नई दर इस प्रकार हैं:
आजीवन पॉलिसियाँ:
रु. 77.50 प्रति रु. 1000/- बीमित राशि प्रति वर्ष.
बन्दोबस्ती पॉलिसियाँ:
रु. 62.00 प्रति रु. 1000/- बीमित राशि प्रति वर्ष.

इसके अलावा योग्य पॉलिसियों पर अंतिम (अतिरिक्त) बोनस भी.
जीवन बीमा पॉलिसी अब पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक है.
तो आज ही, अधिक जीवन बीमा करवाने की योजना बनाएं.

भारतीय जीवन बीमा निगम
जनता की सेवा में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

R K SWAMY/LIC/1738 HN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूरदर्शन

सरकार का कसता शिकंजा

पिछले पखवाड़े दूरदर्शन के महानिदेशक भास्कर घोष के अचानक तबादले से नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित छोटे परदे के बड़े दफ्तर में भूचाल आ गया. तबादले का मकसद साफ था—चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी टीवी जैसे शक्तिशाली माध्यम पर अपना शिकंजा कसना चाहती है. प्रमुख संवाददाता मधु जैन की रिपोर्ट:

'यस प्राइम मिनिस्टर' सीरियल देखा था आपने? यह तमाशा भी वैसा ही है. लेकिन हास्य का पुट इसमें से नदारद है. पिछले पखवाड़े दूरदर्शन से महानिदेशक भास्कर घोष की अचानक विदाई बताती है कि इस सरकारी प्रचार माध्यम में वही होता है जो प्रधानमंत्री और उनके सरपरस्तों को पसंद हो और मुआफिक लगे.

तीन अक्तूबर को घोष के तबादले से समाचार जगत की भृकुटियां तन गईं. धड़ाधड़ छपे संपादकीयों का सुर था कि छोटे परदे पर 'ग्लासनोस्त' (खुलेपन की नीति) की भ्रूणहत्या कर दी गई है. घोष की छुट्टी जिस जल्दबाजी में की गई, उसे देख मंडी हाउस और नौकरशाही को जैसे पाला ही मार गया.

लेकिन घोष को हटाए जाने के शोरगुल में एक तथ्य की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया. दरअसल घोष को उनके कामकाज के कारण नहीं बल्कि इसलिए हटाया गया कि सरकार संकट और परीक्षा की इस घड़ी में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती. यह जमाना है प्रचार, जनसंपर्क और सस्ती लोकप्रियता बटोरने का और टीवी तो छवि बनाने का आदर्श माध्यम है. इसलिए दूरदर्शन के नए कार्यक्रम में प्रचार और प्रसिद्धि पाने को तरजीह दी जा रही है.

हो सकता है कि सारे कार्यक्रम कृषि दर्शन की तरह के न हों, लेकिन 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' वाले सरकारी वृत्तचित्रों का बोरियत भरा जमाना तो लौट ही रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र की भी बियाबान से वापसी होगी लेकिन पहले से कहीं ज्यादा तड़क-भड़क के साथ.

अब छोटे परदे पर मंत्रियों की शक्लें ज्यादा दिखाई देंगी. खबरों में इसकी झलक तो मिलने भी लगी है. और 'प्रधानमंत्री दर्शन' सामान्य से कई गुना बढ़ जाएगा. 'रामायण' की अपूर्व सफलता के बाद सरकार ने बलदेव राज चोपड़ा के 'महाभारत' को परदे पर उतारने को हरी झंडी दिखा दी. अब मुल्क को गम गलत करने के लिए धर्म की एक और खुराक मिल रही है.

छोटे परदे के पीछे छिपे 'प्रतिभाशाली लोग' अब शहरी दर्शकों को दी जा रही प्राथमिकता को जरा किनारे रख गांवों की ओर भी ध्यान देंगे. सूचना और प्रसारणमंत्री हरकिशनलाल भगत ने 'इंडिया टुडे' से कहा, "भारतीय समाचार जगत को लोगों के करीब आना चाहिए... भारतीय टेलीविजन को भारतीय बनाना होगा. और यही नहीं, मैं सूचना और लोकप्रियता में कोई विरोधाभास नहीं देखता."

यानी लोगों के ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन

कार्टून: अजीत नैनन

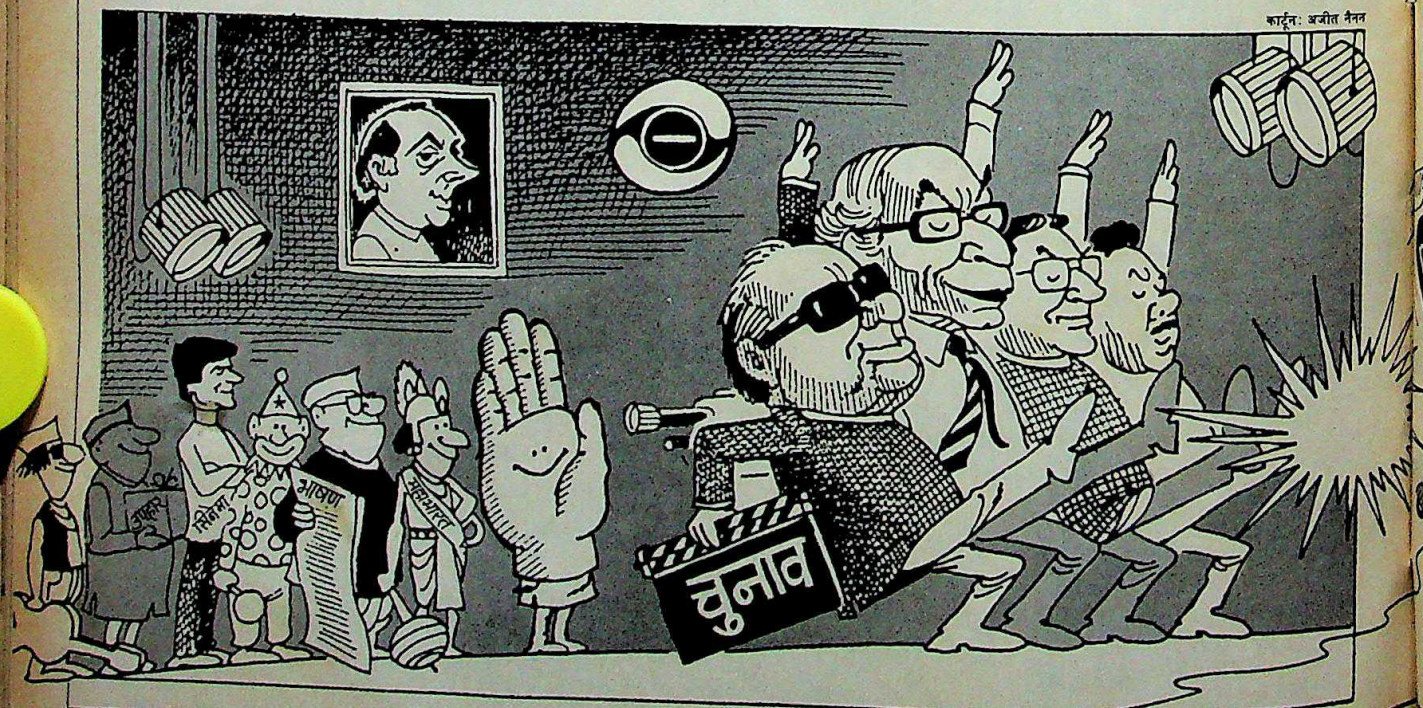

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

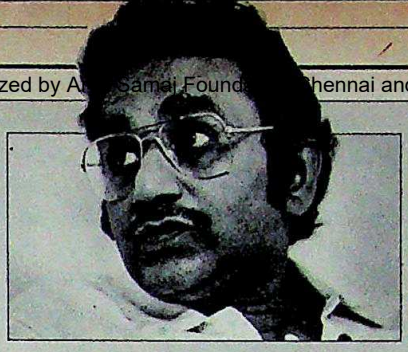

कृष्ण कुमार

'उपलब्धियों को दिखाना ही होगा'

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कृष्ण कुमार का मानना है कि भारतीय दूरदर्शन को विवादों में उलझने की जरूरत नहीं. उसे सीधे-सीधे देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना चाहिए. उनके मुताबिक देश को आज आत्मविश्वास की जरूरत है और टीवी का इस्तेमाल इसी मकसद से किया जाना चाहिए. पिछले पखवाड़े प्रमुख संवाददाता ***मधु जैन*** *से हुई बातचीत के कुछ अंश :*

• आपके नजरिये में टीवी की क्या भूमिका है?

मेरा मत है कि भारतीय होने पर गर्व का भाव जगाना टीवी का काम है. हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, नियोजित अर्थव्यवस्था और विकास के मूल्यों पर जोर देना होगा. आत्मप्रवंचना के बजाय हमें 40 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों को दिखाना होगा.

• तो क्या आलोचना करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा?

आलोचना पर परदा नहीं डाला जाएगा. इसकी गुंजाइश रहेगी. पर सरकार को भी खंडन करने का अधिकार है.

• लेकिन क्या सरकार की उपलब्धियां बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताई जा रहीं हैं?

इतना ही काफी नहीं है. कृषि उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र छूट रहे हैं. हमें सार्वजनिक क्षेत्र, अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा अपने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अहमियत देनी चाहिए.

• शंका जाहिर की जा रही है कि दूरदर्शन में बदलाव का जो झोंका आया था, अब उसका दौर खत्म होने को है.

हमने अपनी नीति में कतई कोई तब्दीली नहीं की है.

• लेकिन अब टीवी पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के चेहरे दिखाई देना अचानक ही बढ़ गया है. क्या ये आने वाली तब्दीलियों के संकेत हैं?

प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान कर्ताधर्ता होने के अलावा नीति-निर्धारण का सर्वोच्च अगुआ भी है. जब वे कोई नीतिगत घोषणा करते हैं तो यह खबर अहम होती ही है.

• अमूमन मंत्री तो उद्घाटन करते ही दिखाई देते हैं.

अगर यह विकास प्रक्रिया का हिस्सा हो तो इसे दिखाना ही होगा.

• कुछ साल पहले दूरदर्शन को स्वायत्ता देने की चर्चा थी. क्या अब यह मुद्दा अप्रासंगिक हो गया है?

दूरदर्शन को पर्याप्त स्वायत्ता है. निदेशक के पास काफी अधिकार हैं.

की व्यवस्था करो और बीच-बीच में मंत्रियों के चेहरे और 'राष्ट्र-निर्माण' की झलक दिखाते जाओ. इसीलिए हर हफ्ते दो हिंदी फिल्में दिखाने की घोषणा की गई है. इसके अलावा और अधिक हास्य धारावाहिक और रंगारंग संगीत कार्यक्रम भी दिखाए जाने की योजना है. लेकिन इसमें शायद वह सारा कुछ नहीं होगा जिससे पिछले कुछ महीनों से लोगों का जायका बदलना शुरू हो गया था.

बदलाव की छोटी लहरें, जिसे कइयों ने 'ग्लासनोस्त' कहा, शास्त्री भवन से बही थीं, मंडी हाउस से नहीं. सामयिक मामलों के कुछ कार्यक्रमों में शामिल एक निर्माता ने इन कार्यक्रमों के खुलेपन का सेहरा घोष के सिर बांधे जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया. उसने कहा, "यह बखेड़ा मेरी समझ से परे है. हर चीज पर गोपी अरोड़ा ने मंजूरी दी. शास्त्री भवन से हमें सीधे बुलावा आता था."

सती पर 'मीडियास्टॉर्म' का विवादास्पद कार्यक्रम, जिसमें लगा कि परेशान से गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम की घेराबंदी कर दी गई हो, सूचना और प्रसारण सचिव की मंजूरी से ही परदे पर आया. इस साल बोफोर्स, विपक्षी एकता, एमजीआर के बाद तमिलनाडु, गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा आंदोलन, दिल्ली में हैजा, मानहानि विधेयक और कई दूसरे कार्यक्रमों को भी मंत्रालय ने ही हरी झंडी दिखाई थी. स्पष्ट है कि सरकारी प्रचार माध्यम के कर्ताधर्ता दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश में लगे थे.

घोष को इतना अचानक और इस तरह क्यों हटना पड़ा? घोष के हटाए जाने के लक्षण दो महीने पहले से ही दिखाई पड़ रहे थे. घोष के नजदीकी सूत्रों का मानना है कि उनके हटाए जाने की मुख्य वजह दूरदर्शन पर इलाहाबाद उपचुनाव और राष्ट्रीय मोर्चे का गठन प्रमुखता से दिखाया जाना है.

घोष सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की नजर में उस समय और भी गिर गए जब 4 सितंबर को विवादास्पद मानहानि विधेयक वापस लिए जाने संबंधी प्रधानमंत्री की घोषणा एक ओडिया फिल्म रोककर प्रसारित की गई. विधेयक वापस लिए जाने की घोषणा सेवा दल की बैठक में की गई. इसका मकसद यह जताना था कि विधेयक वापसी का फैसला सरकार ने नहीं बल्कि पार्टी ने किया है. भगत तुरंत संसद मार्ग स्थित दूरदर्शन केंद्र पर गए और तकनीशियन से 'सब कुछ रोककर घोषणा की रिकार्डिंग प्रसारित करने' को कहा. लेकिन 14 मिनट का वीडियो मिट गया था. इसलिए सारे देश के लोगों ने सिर्फ यह देखा कि राजीव गांधी मुट्ठीभर टोपीधारी सेवा दल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं.

इस पर कुपित भगत ने दोषी लोगों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए. जांच के दौरान घोष ने बार-बार कहा कि इसके लिए तकनीशियन दोषी नहीं हैं. फिर, एक और घटना हुई जिसने महानिदेशक की रवानगी की रफ्तार और तेज कर दी. प्रधानमंत्री 'नेशनल हेराल्ड' की रजत जयंती पर भाषण दे रहे थे. भाषण के दौरान मानहानि विधेयक के खिलाफ लगने वाले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नारों के बीच प्रधानमंत्री की आवाज लगभग डूब गई थी. स्पष्टतः, कैमरा दल को नारे रिकार्ड करने के लिए कहा गया था. उसके पीछे मकसद यह था कि प्रधानमंत्री इन नारों के दौरान जो टिप्पणी करेंगे, वह उनका जवाब होगा. लेकिन दूरदर्शन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल न किए जाने के कारण गड़बड़ी हो गई और प्रधानमंत्री की आवाज नारों में डूब गई.

छवि बनाने वालों का मानना है कि चुनाव के समय दूरदर्शन का आधुनिकीकरण और बढ़िया प्रस्तुति वक्त की जरूरत है. दूरदर्शन जल्दी ही 85 फीसदी लोगों तक पहुंचेगा. महत्वपूर्ण यह है कि इस काम में उनके पास पहले जैसा ही एक उपयुक्त आदमी है. भगत 1984 में सूचना और प्रसारणमंत्री थे तो देश में तेजी से ट्रांसमीटर लगाए गए. फिलहाल देशभर में 260 ट्रांसमीटर हैं और सातवीं योजना तक 420 हो जाएंगे. चुनावों के करीब आने तक दूरदर्शन कांग्रेस (इ) का संदेशवाहक बनेगा.

तकनीक

मशीनों का महातम

सबसे पहले महावर लगे पांव थिरकते हुए दिखते हैं. फिर अभिनय में तल्लीन आंखें, पल भर बाद नमस्कार की मुद्रा में झुका हुआ चेहरा. परदा तीन चलायमान छवियों वाले वर्गों से भर जाता है और कथक नृत्य भी किसी कंप्यूटरी पहेली की तरह नजर आने लगता है. यह सब करामात है दूरदर्शन के केंद्रीय निर्माण केंद्र में आए उपकरणों की. यह केंद्र दिल्ली के सिरी फोर्ट खेलगांव में है. पर आज तक जाने क्यों इसका उद्घाटन टलता जा रहा है.

भास्कर घोष ने कोशिश की थी कि दूरदर्शन सिर्फ दूसरों के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दे बल्कि खुद भी रचयिता का रोल अदा करे. दूसरे केंद्रों के प्रोड्यूसर भी यहां लाए गए. केंद्र के लिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या 350 है. 120 का स्टॉफ हो गया है. इसने धारावाहिकों और टेलीफिल्मों का निर्माण भी शुरू कर दिया. आजकल एंटोन चेखव की प्रसिद्ध कहानी 'टिड्डा' पर एक टेलीफिल्म का निर्माण चल रहा है. अगले आठ महीनों में यहां दो धारावाहिक, चार वृत्तचित्र और दो टेलीफिल्मों का निर्माण होगा.

लेकिन केंद्र के ये निर्माण दूरदर्शन के मौजूदा कार्यक्रमों या बंबइया फिल्मों से विषयवस्तु के मामले में नहीं बल्कि स्तर के मामले में अलग होंगे. केंद्र के निदेशक गोपाल सक्सेना बताते हैं, "हमारे उपकरण बहुत बढ़िया हैं और इसकी तुलना यूरोपीय देशों के उपकरणों से की जा सकती है."

इस केंद्र में दो बड़े-बड़े स्टुडिओ हैं जिनका क्षेत्रफल करीब 400 वर्गमीटर है. इन दोनों में चार अति आधुनिक वीडिओ कैमरे लगे हैं. पर सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है एडीओ-2000 जो कार्यक्रम की प्रस्तुति में असली तकनीकी कलाबाजी दिखाता है. इसी से कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान खास असर भी पैदा किए जाते हैं. इंजीनियरिंग विभाग के एस.एस. स्वामी बताते हैं, "हम पूरी तस्वीर को

दूरदर्शन का केंद्रीय निर्माण केंद्र

एक बिंदु में सिमटा सकते हैं. चित्रों को मनमाना आकार और स्थान दे सकते हैं. साथ ही हम तस्वीरों को ऊपर-नीचे, बाएं-दाएं नचा भी सकते हैं."

इस केंद्र में व्यक्तियों की नहीं, मशीनों की तूती बोलती है. आस्ट्रेलियाई अभिनेता रॉबिन रामसे ने रवींद्रनाथ ठाकुर के जीवनदर्शन पर एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसका यहां फिल्मांकन हो रहा है. लाल लबादा पहने रामसे एक भव्य मेज के पीछे बैठे हैं. उनका सामना सिर्फ कैमरे और कैमरामैन भर से है. बाकी सारी दृश्यावली अदृश्य रूप से चित्रित हो रही है. इस केंद्र में लगे कंप्यूटर नियंत्रित बल्ब भी अद्भुत हैं जो तय कार्यक्रम के अनुसार तेजी और मद्धिम रोशनी देते तथा बुझ जाते हैं. नियंत्रण कक्ष ऊपरी मंजिल पर है और सारा काम वॉकी-टॉकी के जरिये होता है. किसी दृश्य की प्रकाश संयोजना को कंप्यूटर की स्मृति में भरा जा सकता है. इन उपकरणों के अनंत संभावनाओं से उत्साहित एक प्रोड्यूसर कहते हैं, "अगर अमिताभ बच्चन की तरह का कोई व्यस्त अभिनेता यहां की किसी फिल्म में काम कर रहा हो और दोबारा जल्दी न आने वाला हो तो हम किसी या सभी दृश्यों की प्रकाश संयोजना कंप्यूटर की स्मृति में डालकर और जब अभिनेता फिर आए तो उससे काम ले सकते हैं."

वीडियोग्राफी वाली मशीन क्वांटेल पेंटबॉक्स भी एक अलग ही चीज है. (यह वह सारा काम कर सकती है जो कलाकार कूची, रंग और पेंसिलों से करते हैं). इलेक्ट्रॉनिक दृश्यों को संभालकर रखने वाला डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम भी काफी काम का उपकरण है.

सो, अब भारतीय संस्कृति को बैलगाड़ी वाली रफ्तार में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं. अब इसे भी पॉप संगीत वाली चमक-दमक के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है. आखिर 21वीं शताब्दी भी तो आने वाली है.

—मधु जैन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूचियों की राजनीति

मध्य प्रदेश इंका के दफ्तर में धमाका होने ही वाला है. मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने प्रदेश इंका अध्यक्ष चंदूलाल चंद्राकर को अपराधी या 'आपराधिक पृष्ठभूमि' वाले लोगों की एक सूची भेजी है. ये कथित आर्थिक अपराधी और जमीन हड़पने वाले लोग मोतीलाल वोरा के शासनकाल में 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों में जगह पा गए थे. ये सभी चूंकि पार्टी के 'सम्मानित' सदस्य हैं इसलिए उनका नाम समितियों से हटाने से पहले अर्जुन सिंह ने पार्टी प्रमुख से अनुमति लेना जरूरी समझा. मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी कि अपने राजनैतिक रिश्तों की मदद से ये अवांछनीय तत्व इन शक्तिशाली कमेटियों में घुस गए हैं.

भवान सिंह

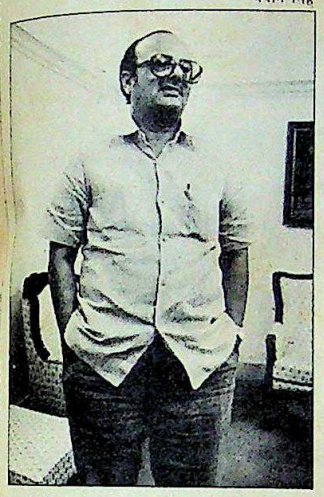

अर्जुन सिंहः सफाई अभियान

असंतुष्ट गुट भी कहां पीछे रहने वाला था. उसने आलाकमान के पास ऐसे दुष्चरित्र लोगों की सूची भेजी है जिन्हें अर्जुन सिंह के खासमखास दिग्विजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रहते समय पार्टी में पदाधिकारी नियुक्त किया था. सूची के साथ लगे ज्ञापन में इन लोगों की पहले की सारी करतूतों का विवरण भी है. इनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, धोखाधड़ी, अपराधियों के संगठित गिरोह चलाने जैसे अपराध भी शामिल हैं. इन्हें देखकर यही लगता है कि इटली के माफिया सरदार भी कांग्रेसियों के आगे पानी ही मांगते दिखेंगे.

ल से लंदन ल से लखनऊ

लंदन-नई दिल्ली के बीच एक अजीब तरह का रिश्ता बनता नजर आ रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों के मामले में. कुछ मामलों में तो दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए दिल्ली-लंदन सबसे 'छोटा' रास्ता बन गया है. ऐसा सबसे पहले नारायणदत्त तिवारी के साथ हुआ. 23 जून को जब वे केंद्रीय वित्तमंत्री की हैसियत से कुछ देशों का दौरा करते लंदन पहुंचे ही थे कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा मिला. 25 जून को लंदन से उनकी वापसी सीधे लखनऊ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही हुई.

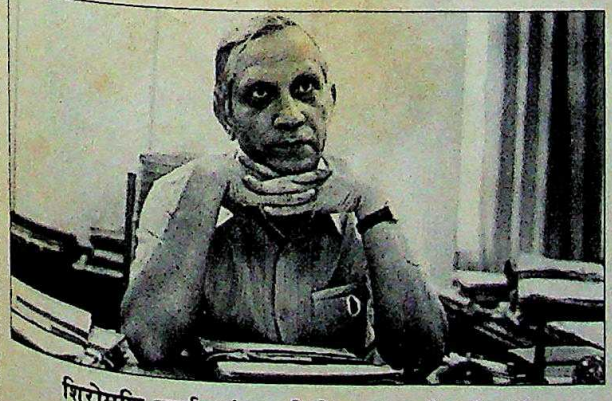

शिरोमणि शर्माः लंदन की प्रेत-बाधा की चपेट में

संयोग से उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव शिरोमणि शर्मा के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ. 27 सितंबर को वे केंद्रीय कपड़ा सचिव की हैसियत से विदेश यात्रा पर निकले. अगले दिन लंदन पहुंचते ही उन्हें दिल्ली से बुलावा मिल गया. उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था. लेकिन शर्मा ने अपनी यात्रा अधूरी नहीं छोड़ी. सो, यात्रा पूरी करने के बाद 12 अक्तूबर को लखनऊ पहुंचकर उन्होंने नया कार्यभार संभाल लिया. अब लंदन में पदस्थापित उत्तर प्रदेश काडर के एक पुलिस अधिकारी को दिसंबर में राज्य पुलिस का प्रमुख बनाए जाने की चर्चा है. वर्तमान पुलिस प्रमुख आर.एन. गुप्त तभी अवकाश प्राप्त कर रहे हैं. और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर लखनऊ की यात्रा का 'शार्ट कट' लंदन ही साबित होगा. राज्य के एक अधिकारी ने कहा, "लंदन प्रेत बाधा वाला शहर लगता है."

लोगों से मिलने का मौसम

आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन निर्माणमंत्री के. जंगा रेड्डी का मकसद तो नालगोंडा जिले (क्षेत्रफलः 14,240 वर्ग किमी; जनसंख्याः 25 लाख) की पदयात्रा करना था पर उन्हें जल्दी ही इसे 'कार यात्रा' का रूप देना पड़ा. रेड्डी सिर्फ सड़कों और भवनों के निरीक्षण की रस्म अदायगी भर के लिए नहीं जाना चाहते थे. उनकी मंशा दरअसल चुनाव से साल भर पहले ही मतदाताओं से संपर्क साधने की थी. रेड्डी कहते हैं, "मेरी यात्रा का उद्देश्य समस्याओं का पता लगाना, उनको दूर करने के तरीके ढूंढ़ना है." असल योजना 2 अक्तूबर से 22 नवंबर के बीच 51 दिवसीय

नालगोंडा में 'कार यात्रा' पर निकले जंगा रेड्डी

पदयात्रा की थी जिसमें वे 500 गांवों में जाते. इसकी तैयारी के लिए रेड्डी दो हफ्तों तक रोज सुबह दौड़ने भी निकलते थे.

लेकिन यह पदयात्रा शुरू ही नहीं हो पाई. यात्रा शुरू होने के चार दिन पहले मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव ने उनसे राजधानी में ही रहने को कहा क्योंकि धान की कीमत और चावल मिलों के लिए खरीद के बारे में फैसला करने वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति में वे भी सदस्य हैं. मुख्यमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि वे हर इतवार को कार से अपने क्षेत्र की यात्रा किया करें. हारकर रेड्डी ने गांधी जयंती के दिन से अपनी 'कार यात्रा' शुरू की.

इस दौरान वे जमीन और कर्ज देने वाले कागजात बांटेंगे और गांववालों से उनकी शिकायतों की अर्जियां लेंगे. रेड्डी ने कहा, "अपने जिले के लोगों से मिलने का यह सबसे बढ़िया समय है. आजकल वे धान लगाकर निश्चित हैं और नवंबर में ही फिर काम में व्यस्त हो पाएंगे. अगर यही यात्रा मैं अगले साल करता तो सभी इसे चुनावी स्टंट बताते." वैसे रामराव को शायद लग चुका है कि इस तरह के स्टंट का वक्त आ गया है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नफा

■ सरदार सरोवर और नर्मदा सागर से 20 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और 2500 मेगावाट बिजली पैदा होगी

"यह नदी गुजरात की जीवन रेखा है. हम पर्यावरणवादियों की बकवास सहन नहीं करेंगे"

चिमनभाई पटेल
जनता पार्टी

पूरा हो रहा पहला बड़ा बांध

नर्मदा घाटी परियोजना

विरोध की घ

अपनी तरह की सबसे बड़ी और महंगी नर्मदा घाटी विकास परियोजना को मंजूरी मिलने के आसार दिखते ही विरोध के स्वर तीखे होने लगे हैं. राजनीतिकों और पर्यावरणवादियों में ठन-सी गई है. इस कारण परियोजना अधर में फंसती दिख रही है. एक रिपोर्ट:

परियोजना के हिमायतियों के अनुसार यह इंजीनियरिंग का नायाब नमूना होगी, यह मध्य भारत का नक्शा बदलकर रख देगी और देश को दूसरी हरित क्रांति के प्रवेश-द्वार पर खड़ा कर देगी. दूसरी ओर इसके विरोधियों का दावा है कि पर्यावरण को तबाह करने की इससे बड़ी योजना-बद्ध कोशिश दुनिया में और कहीं नहीं हुई. देश के पर्यावरणवादियों और योजनाकारों को एक दूसरे से भिड़ाने वाली इस सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद नदी घाटी परियोजना का नाम है—नर्मदा घाटी विकास परियोजना.

करीब 40,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत नर्मदा और इसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले और 3,000 से ऊपर छोटे बांध बनाए जाएंगे. मध्य प्रदेश के अमरकंटक से चलने वाली नर्मदा करीब 1,312 किमी दूरी तय करती, हरे-भरे जंगलों से गुजरती, दुर्गम पहाड़ों और घाटियों को लांघती गुजरात में अरब सागर से जा मिलती है.

करीब 40 वर्षों की सार्वजनिक बहस के बाद केंद्र सरकार ने नर्मदा पर प्रस्तावित दो विशाल बांधों में से एक के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी. इस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में बनेगा. दूसरे, मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है. इन दोनों बांधों से गुजरात और मध्य प्रदेश मे 20 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 2.500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी. लेकिन साथ ही ये अभूतपूर्व पर्यावरणीय और मानवीय संकट भी खड़े करेंगे.

प्रस्तावित नर्मदा सागर जलाशय दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील होगी. इसके पानी में 40,000 हेक्टेयर सागौन के जंगल और करीब इतनी ही खेती लायक जमीन डूब जाएगी. और

पल्लव बागला

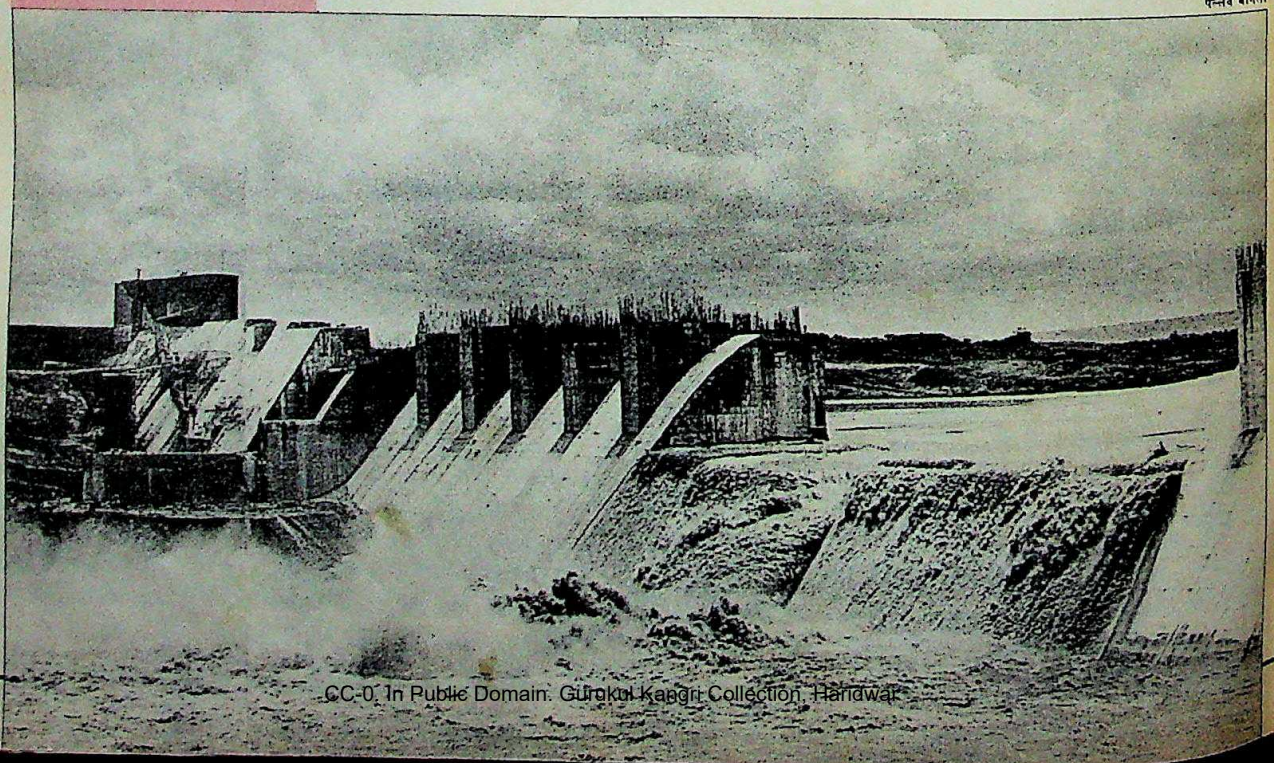

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की घनी घाटियों में

गुजरात में सरदार सरोवर भी 40,000 हेक्टेयर जमीन को जलप्लावित कर देगा. इन दोनों बांधों के कारण 500 गांवों के करीब दो लाख लोग बेघर हो जाएंगे.

पिछले महीने 100 से भी ज्यादा विज्ञानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणवादियों ने परियोजना को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ज्ञापन दिया और इस पर फिर से विचार करने की अपील की. ज्ञापन पर दस्तखत करने वालों में बाबा आमटे, एम.एस. स्वामीनाथन, सतीश धवन और अनिल अग्रवाल भी शामिल हैं. ज्ञापन में कहा गया है कि परियोजना से होने वाली तबाही का सही आकलन नहीं किया गया, कि यह तबाही दोनों बांधों की अनुमानित लागत से कहीं ज्यादा होगी. और फिर परियोजना की वजह से उजड़ने वाले दो लाख लोग कहां बसाए जाएंगे यह पक्का नहीं किया गया है.

पिछले महीने के इस ज्ञापन से जो विवाद खड़ा हुआ है वह उसी तरह के आंदोलन का रूप ले सकता है जो सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में चला था. राजनीतिकों में पहले से ही दहशत व्याप्त है. जनता पार्टी के चिमनभाई पटेल कहते हैं, "यह नदी गुजरात की जीवन रेखा है. हम पर्यावरणवादियों की कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे."

इसमें संदेह नहीं कि परियोजना के कई फायदे

रमा वी.के. शर्मा

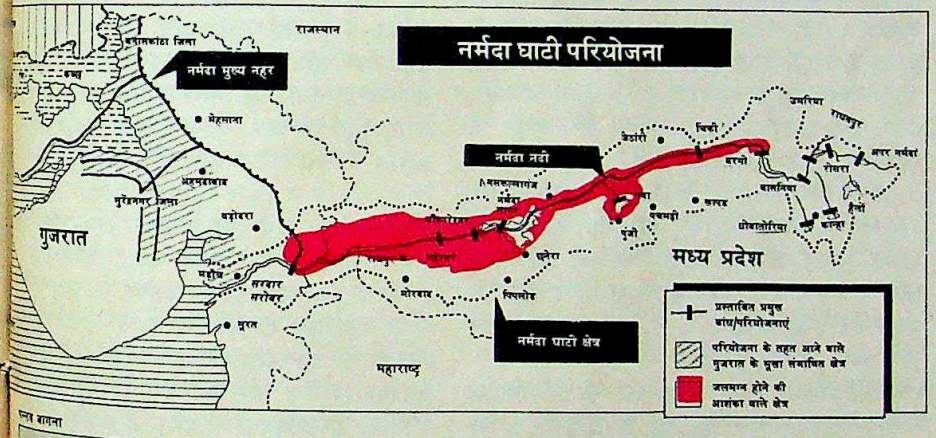

पल्लव बागला

नुकसान

■ **500 गांवों के दो लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे और उनके पुनर्वास के लिए अभी तक जमीन तय नहीं की जा सकी है**

"मध्य प्रदेश सरकार को पुनर्वास के लिए 35,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. लेकिन सारी खाली जमीन पर अवैध कब्जा है"

लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल
अध्यक्ष, नर्मदा सागर संघर्ष समिति

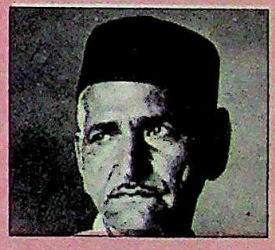

विस्थापन के खिलाफ वनवासियों का प्रदर्शन

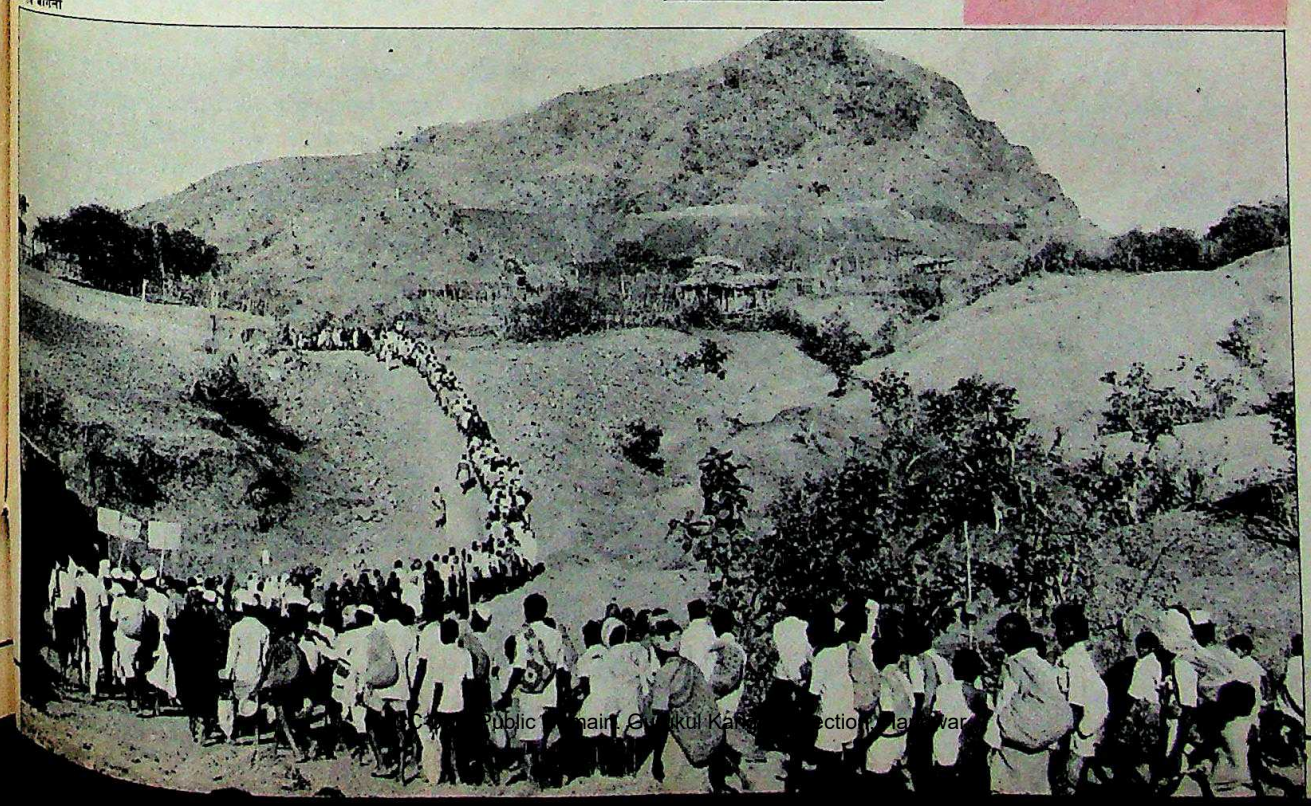

CC-0. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नफा

■ हरदम सूखा झेलने वाले गुजरात में सरदार सरोवर 18 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करेगा और 131 शहरों तथा 4720 गांवों को बिजली और पानी मुहैया कराएगा

"नर्मदा परियोजना ही एकमात्र समाधान है. इस पर बेहिसाब बहस हुई, काफी जांच-पड़ताल हुई पर इसे लागू करने का काम बहुत कम किया गया"

सनत मेहता,
अध्यक्ष, सरदार सरोवर
नर्मदा निगम

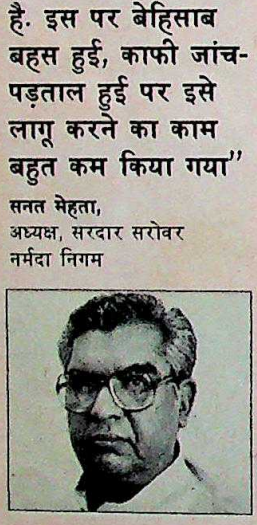

पानी लाने के लिए मीलों तक जाती वनवासी औरतें

हैं. अकेले गुजरात के सूखा वाले क्षेत्रों में ही सरदार सरोवर से 18 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी, राज्य के 19 में से 12 जिलों के 131 कस्बों और 4,720 गांवों को पानी भी मिलेगा और बिजली भी. नर्मदा सागर से हालांकि मध्य प्रदेश को तुरंत तो कोई फायदा नहीं होगा, पर परियोजना से कृषि को भारी प्रोत्साहन मिलेगा.

सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अध्यक्ष और गुजरात के पूर्व वित्तमंत्री सनत मेहता का तर्क है, "नर्मदा परियोजना ही एकमात्र समाधान है. इस योजना पर बेहिसाब बहस तो हुई है और कई पहलुओं से इसे परखा गया है पर इसे लागू करने के लिए बहुत काम नहीं किया गया." योजना आयोग के सदस्य डॉ. वाई.के. अलघ कहते हैं, "सरदार सरोवर परियोजना की लागत और लाभ के समीकरण का खासा विश्लेषण हुआ है और नदी के पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की योजना बनाई गई है."

पर्यावरणवादी भी मानते हैं कि परियोजना फायदेमंद हो सकती है. लेकिन उनकी आपत्ति पर्यावरण की संभावित तबाही पर ही नहीं है, राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की आपत्तियों के जवाब में चुनींदा आंकड़ों, बेबुनियाद दावों और राजनैतिक लाभ-हानि के बहाने पेश करने पर आपत्ति है.

पर्यावरण मंत्रालय की स्पष्ट टिप्पणी है, "निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो पर्यावरण के पहलू से नर्मदा सागर परियोजना अभी मंजूरी के लायक नहीं है." एक अंदाज के मुताबिक दोनों बांधों से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 39,000 करोड़ रुपए मूल्य का नुकसान होगा.

मध्य प्रदेश सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने में इसलिए आनाकानी कर रही है कि इससे ज्यादा फायदा गुजरात को ही मिलना है. गुजरात इसी कारण अधिक जोर दे रहा है. गुजरात इसलिए भी जोर दे रहा है कि बांध बन जाने से इसके 60 फीसदी जिलों को सूखे से मुक्ति मिल जाएगी.

पल्लव बागला

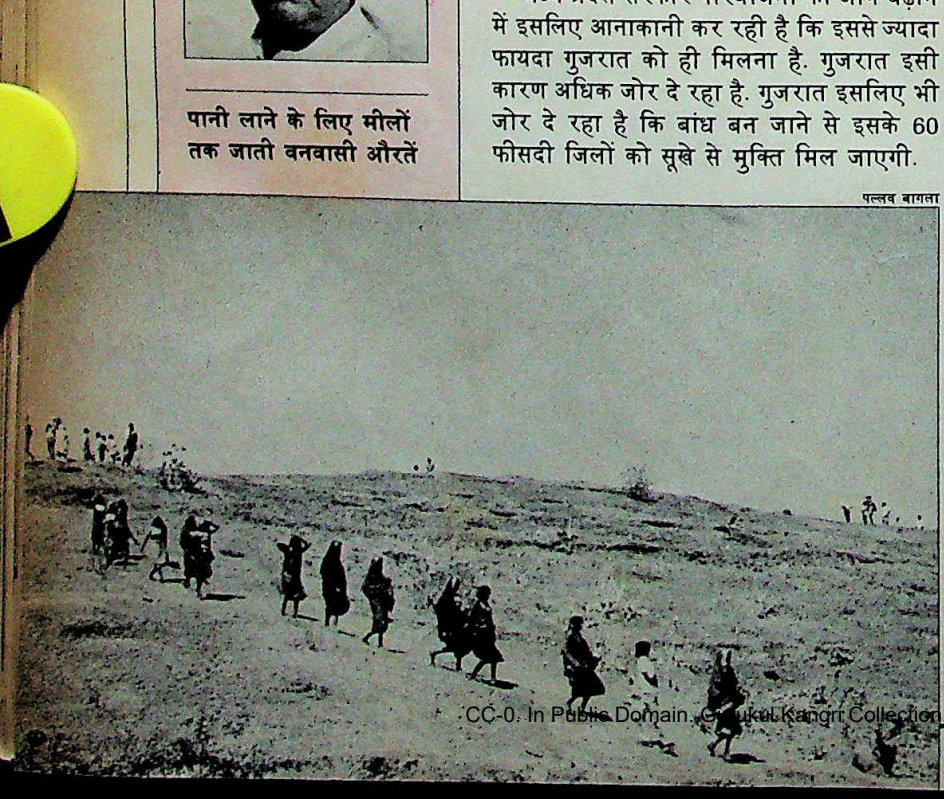

पर असलियत कुछ और ही है. परियोजना के तहत आने वाले 12 जिलों में से खेड़ा, वडोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर अच्छी सिंचाई सुविधा वाले इलाकों में हैं. यह दावा भी संदेहास्पद है कि सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी.

लागत की तुलना में लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर गुजरात अपने तर्क मजबूत करना चाहता है. योजना आयोग के मुताबिक किसी बांध परियोजना से लाभ लागत का कम-से-कम डेढ़ गुना होना चाहिए. सरदार सरोवर के लिए राज्य सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की सेवाएं लीं, जिसके हिसाब से इसमें लागत व लाभ का अनुपात 1:1.84 रहेगा. पर यह विश्लेषण भी सही नहीं है. लागत का अनुमान 1981-82 के आंकड़ों पर आधारित है, तब से लागत दूनी हो गई होगी. सर्विस ने मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा सिंचाई क्षमताओं के विकास की संभावनाओं पर भरोसा किया है. मगर राज्य सरकार के अनुमानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता. साथ ही लागत में पर्यावरण के घाटे का हिसाब-किताब नहीं रखा गया है, सिर्फ वन उत्पादों के मामले में राजस्व हानि को ही उसमें शामिल किया गया है. साथ ही पैदावार बढ़ने संबंधी अनुमान भी यथार्थ पर आधारित नहीं हैं.

परियोजना के योजनाकारों ने कुछ और फायदों की भी खोज की है ताकि लागत-लाभ अनुपात 1:1.84 के बजाय 1:2 बताया जा सके. नए लाभ हैं— ताप विद्युत के बजाय जल विद्युत के इस्तेमाल से कई मदों पर खर्च में 13,000 करोड़ रुपए की बचत; और साथ ही औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से 14,441 करोड़ रु. की आमदनी.

लेकिन परियोजना से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास की गंभीर समस्या के मामले में दोनों सरकारों की सारी पोल खुल जाती है. मानदंडों के हिसाब से, अगर गांव वाले चाहें तो राज्य सरकार को गांव जस का तस फिर से बसाना होगा. इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार के रवैये से खफा होकर परियोजना की सबसे अहम नियंत्रक इकाई, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एस.सी. वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है.

मध्य प्रदेश में कई विरोध प्रदर्शनों और ज्ञापनों के बाद लोगों ने असहयोग शुरू कर दिया. डूब वाले इलाकों के गांवों में सरकारी सर्वे दलों का घुसना मुश्किल कर दिया गया है. नर्मदा सागर परियोजना के आसपास रहने वाले आदिवासी गुजरात जाने को राजी नहीं हैं. उनके लिए वह अनजान इलाका है, जहां वे अपने सांस्कृतिक परिवेश से कट जाएंगे, जातीय रूप से अलग-थलग पड़ जाएंगे. एक किसान मोहम्मद हैदर कहते हैं, "हम कहीं नहीं जाना चाहते. हम महंगी जमीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं चाहते. सरकार हमें मजबूर कर रही है.''

सरकार के पास पर्याप्त जमीन भी नहीं है. उसे 35,000 एकड़ जमीन चाहिए पर सरकारी कागजात के हिसाब से उसके पास महज 24,000 एकड़ जमीन ही है. नर्मदा सागर संघर्ष समिति के अध्यक्ष एल.एन. खंडेलवाल कहते हैं, ''ऐसी करीब सारी खाली जमीन जबरन कब्जे में है.'' गुजरात ने पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश को 12,000 हेक्टेयर जमीन देने का प्रस्ताव किया था पर इसमें से एक-चौथाई जमीन ही खेती के लायक पाई गई.

सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के लिए गुजरात ने एक पुनर्वास योजना घोषित की है. इसके तहत हर विस्थापित परिवार को नकद मुआवजे के अलावा पांच एकड़ जमीन दी जाएगी, बिना इस बात का ख्याल किए कि पहले उसके पास कितनी कानूनी या गैरकानूनी जमीन थी. लेकिन यह योजना कागज पर ही है. करीब दो लाख एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. सरकार तो दावा करती है कि इतनी जमीन उपलब्ध है. मगर वह धोखा दे रही है. नर्मदा संघर्ष समिति की मेधा पाटकर बताती हैं, ''उनके कागजात कहते हैं कि जमीन है, पर जब आप वहां जाते हैं तो पता लगता है कि उस पर तो पहले से ही गैरकानूनी कब्जा है.''

सरदार बांध के लिए 630 करोड़ रुपए का कर्ज देने वाले विश्व बैंक की सलाह है कि पुनर्वास के लिए जंगलों की जमीन इस्तेमाल की जाए. लेकिन यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होगा. विस्थापितों के पुनर्वास का गुजरात सरकार के पास अब एक ही तरीका बचा है कि वह सीधे बाजार से महंगी जमीन खरीदे. इसलिए आश्चर्य नहीं कि जमीन की कीमत आसमान छूने लगी है.

सरकारी जमीन उपलब्ध न होने के कारण दोनों सरकारों ने तय किया है कि अब पेड़ लगाने का काम तबाह हो चुके जंगलों की जमीन पर किया जाएगा. लेकिन यह भी कानून का उल्लंघन ही मान जाएगा.

परियोजना के कारण डूब में आने वाले इलाके के वन्य प्राणियों की कोई गणना तो हुई ही नहीं है. और न ही उनके रहने की जगहों पर मंडराने वाले खतरों का अध्ययन हुआ है. एक दशक पहले नर्मदा परियोजना की अनुमानित लागत 4,000 करोड़ रु. आंकी गई थी. आज सिर्फ सरदार सरोवर की लागत ही 13,000 करोड़ रु. तक आंकी जा रही है. गुजरात इस बात की कोशिश कर रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित कर दिया जाए.

मेहता को विश्वास है कि पैसा तो वे आप्रवासी गुजरातियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राज्य के सरकारी निगमों, निवेश बैंकरों से हासिल कर लेंगे. उनकी योजना जनता तक से पैसा इकट्ठा करने की है. वे कहते हैं कि परियोजना से होने वाली आमदनी से वे इसका ब्याज चुका देंगे. फिर भी 3,000 करोड़ रुपए की कमी रह जाएगी.

गुजरात जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है. उसने डूब में आने वाले इलाके के लिए कोई ठीकठाक योजना भी नहीं तैयार की. बांध की मजबूती बनाए रखने के लिए इस इलाके में भरने वाली गाद को हटाने की व्यवस्था बहुत जरूरी है. डूब वाले इलाके का अनुमानित क्षेत्रफल 47,320 वर्ग किमी से घटाकर 7,919 वर्ग किमी कर दिया गया है. पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, ''यह वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित न होकर, मनमौजी अनुमान पर आधारित है.''

राजनैतिक दबावों के कारण तत्कालीन पर्यावरण सचिव टी.एन. शेषन की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया और परियोजना को जून में मंजूरी दे दी गई. गुजरात में सरदार सरोवर बांध के समर्थन में सभी दलों के लोग दिख रहे हैं. लेकिन नर्मदा सागर बने बिना सरदार सरोवर कारगर नहीं होगा, क्योंकि तभी गुजरात में नदी के पानी की आपूर्ति ठीक होगी. लेकिन मध्य प्रदेश इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा, क्योंकि परियोजना से उसे बहुत कम फायदा मिलेगा.

मंत्रालय ने अब बांधों की ऊंचाई कम करने की सलाह दी है ताकि कम क्षेत्र ही डूब में आएं. लेकिन इससे फायदों के साथ कई नुकसान भी होंगे. बिजली का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा.

लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है इसलिए चुनौतियां भी स्पष्ट हो गई हैं. विस्थापित होने वाले संगठित हो रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणवादी संगठन परियोजना में पैसा न लगाने के लिए विश्व बैंक पर दबाव डाल रहे हैं. कई गणमान्य लोग भी जब इस युद्ध में कूद पड़े हैं तब लगने लगा है कि दोनों राज्यों के लिए इस परियोजना को लागू कर पाना कठिन होता जा रहा है.

—**सलिल त्रिपाठी**, गुजरात में और **नरेंद्र कुमार सिंह**, मध्य प्रदेश में

नुकसान

■ नर्मदा सागर बांध के कारण से 40000 हेक्टेयर वन और 44000 हेक्टेयर खेती की जमीन डूब जाएगी. सरदार सरोवर बांध के कारण 40000 हेक्टेयर जमीन डूबेगी

''हम अपनी जमीन से उजड़कर गुजरात नहीं जाना चाहते. हम महंगी जमीन खरीदना नहीं चाहते. सरकार ही हमें मजबूर कर रही है''

मोहम्मद हैदर
म.प्र. का किसान

परियोजना की चपेट में आने वाला जंगल

CC-0. In

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तस्करी

कंचन की मादक माया

कानून और व्यवस्था कायम करने वाली एजेंसियां पिछले छह महीने से सोना जब्त करने के नए कीर्तिमान बना रही हैं. सरकारी सूत्रों का दावा है कि यह बेशकीमती धातु ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में तस्करी से भारत लाई जा रही है. तस्करों ने इसका एक आसान सौदा खोज लिया है. वे विदेशों से सोना लाते हैं और भुगतान के तौर पर नशीले पदार्थ बाहर भेज देते हैं. वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला ***ने उन गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया जिनमें सोने की तस्करी और नशीले पदार्थों के लेन-देन के अंतरराष्ट्रीय धंधे का ब्यौरा दर्ज है. इनमें धंधे पर दबदबा रखने वाले दुनिया के कुछ सबसे हिंसक अपराधी गिरोहों का भी जिक्र है. उनकी रिपोर्ट:***

देश में तस्करी के जरिये सोना जैसे छप्पर फाड़कर आ रहा है. दूसरी ओर सरकारी एजेंसियां इसे जब्त करने के कीर्तिमान भी तोड़ रही हैं. पिछले छह महीनों में प्रायः हर रोज 3 किलो यानी 10 लाख रुपए मूल्य का तस्करी का सोना बरामद किया जाता रहा. यह सब होता रहा और भारत में सोने की कीमत उछलकर 320 रु. रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गई, जबकि इसकी औसत अंतरराष्ट्रीय कीमत 200 रु. प्रति ग्राम है.

पिछले नौ महीनों में 130 करोड़ रु. मूल्य का 3,900 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जबकि पिछले पूरे साल में विभिन्न खुफिया राजस्व एजेंसियां 2,255 किलो सोना ही बरामद कर सकी थीं. सोने के व्यापारियों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर सोने की बरामदगी सिर्फ इसी वजह से नहीं हुई है कि भारत में इसकी कीमत ज्यादा है बल्कि इसलिए कि इस बीच सोने का पता लगाने के अत्याधुनिक तरीके ईजाद हुए हैं और तस्करों से सोना पकड़ने पर अधिकारियों को पुरस्कार देने की कई योजनाएं लागू हुई हैं. सोना बरामद करने वाले अधिकारी को अब इसके बाजार भाव का 20 फीसदी पुरस्कार के तौर पर नकद दिया जाता है. इसके तहत अभी तक 15 लाख रुपए दिए जा चुके हैं. इसे पूर्व वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शुरू किया था.

लेकिन भारत में तस्करी से लाए जाने वाले सोने की मात्रा में भारी बढ़ोतरी की एक और अहम वजह भी हो सकती है. तस्करों को अब सोना खरीदने के लिए नशीले पदार्थों की बिक्री से पर्याप्त रकम मिल जाती है. सोने और नशीले पदार्थों का यह अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ ही अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है. गोपनीय सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इस धंधे पर दुनिया के सबसे ताकतवर और हिंसक अपराधी गिरोहों का

हशीश भरे थैलों के साथ पुलिसवाले

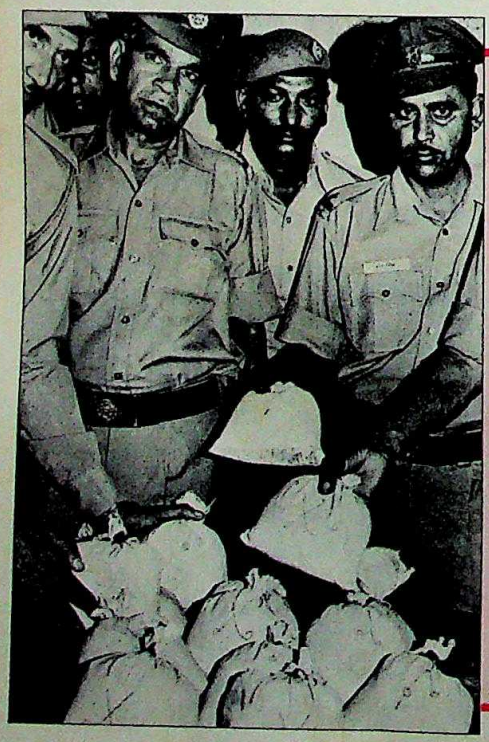

तस्करी से लाए जाने वाले सोने की मात्रा में भारी बढ़ोतरी की एक अहम वजह यह है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से मिलने वाला मुनाफा सोने के रूप में भारत आ जाता है. सोने और नशीले पदार्थों का यह अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ ही अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है

बरामद सोने के साथ अधिकारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बोलबाला है. दरअसल भारत अब पश्चिम को तस्करी से भेजे जाने वाले नशीले पदार्थों के लेन-देन का प्रमुख अड्डा बन चुका है. इन दस्तावेजों के मुताबिक सरकार अंततः इस नतीजे पर पहुंची है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से मिलने वाला मुनाफा सोने के रूप में यहां आ जाता है.

दुनिया भर में आम धारणा यह है कि मुद्रास्फीति से लड़ने का एकमात्र असरदार हथियार सोना ही है. लेकिन भारत में इसका कुछ ज्यादा ही महत्व है, न सिर्फ इसलिए कि शादी-ब्याह और शृंगार वगैरह में इसके इस्तेमाल की परंपरा है बल्कि इसलिए भी कि देश में इसका बहुत ही कम उत्पादन होता है. गौरतलब यह है कि देश में हर साल दो टन सोने से भी कम का उत्पादन होता है. यह इस साल जब्त तस्करी के सोने के आधे से भी कम है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि साल भर में देश में 150 टन सोना अवैध तरीकों से लाया जाता है.

यह तस्करी भी अब परंपरागत हवाई और समुद्री रास्तों या बंबई व गुजरात जैसे केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही है. सीमा शुल्क और राजस्व खुफिया निदेशालय (राखुनि) के अधिकारियों ने देश भर से इसके तस्करों को पकड़ा है—राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से लेकर पंजाब के हरे-भरे खेतों तक से. यह धातु हवाई जहाजों के शौचालय से लेकर ट्रैक्टरों और पेट्रोल टंकियों तक से बरामद की गई है. केंद्रीय आबकारी व सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य (तस्करी निरोधक) बी.वी. कुमार कहते हैं, "भारत में तस्करी से आने वाले सोने की मात्रा बेहताशा बढ़ गई है. लगता है, देश सोने की तस्करी में लिप्त उन गिरोहों के लिए मुख्य बाजार बन गया है जो नशीले पदार्थों में भी उतना ही पैसा लगाते हैं."

सोने के साथ ही नशीले पदार्थों की बरामदगी भी बढ़ी है. 1983 में 'राखुनि' के अधिकारियों ने 139 किलो हेरोइन जब्त की थी जबकि इस साल यह मात्रा बढ़कर 2000 किलोग्राम (देखें चार्ट) हो गई. इस साल अधिकारियों ने 15,000 किलोग्राम से भी ज्यादा हशीश बरामद की जबकि पांच साल पहले यह मात्रा 6,073 किलो थी. नशीले पदार्थों और सोने, दोनों की तस्करी का रास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब व लंदन से होकर गुजरता है. इस साल पकड़े जाने वाले दस में से तीन मामले ऐसे थे जिनमें पाकिस्तानी नागरिक या पंजाब का निवासी जरूर शामिल था.

भारतीय व विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कम-से-कम तीन आपराधिक गिरोह सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं. इसका मुख्य केंद्र भारत बन गया है. इनके तस्करों के अगुआ हैं—पाकिस्तानी नागरिक हाजी अशरफ, बंबई के एक पूर्व माफिया सरदार और अब दुबई में जा बसे दाऊद इब्राहीम शेख और हाजी याकूब अब्दुल्ला.

सोना-नशीले पदार्थ का यह गठजोड़ पहली बार 1982 में उजागर हुआ जब नशीले पदार्थों की आमद भारत में बढ़ने लगी. लेकिन 'राखुनि' को बड़ी कामयाबी 1985 में मिली. तब यह साबित हो गया कि दुबई और लंदन में बैठे दाऊद इब्राहीम, अशरफ और दिवंगत अब्दुल्ला सरीखे लोग भारत के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी के मुख्य सूत्रधार हैं. 13 सितंबर 1985 को भेदियों ने बंबई में जोगेश्वरी से विदेशी छापे वाला 14,000 तोला सोना और 4.77 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा जब्त की.

और इसी साल जुलाई में 'राखुनि' ने 10 लोगों को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया और उनसे 2.78 करोड़ रु. का सोना बरामद किया. उत्तर भारत में यह अब तक का रिकार्ड है. गिरफ्तार किए गए 10 में से 4 लोग

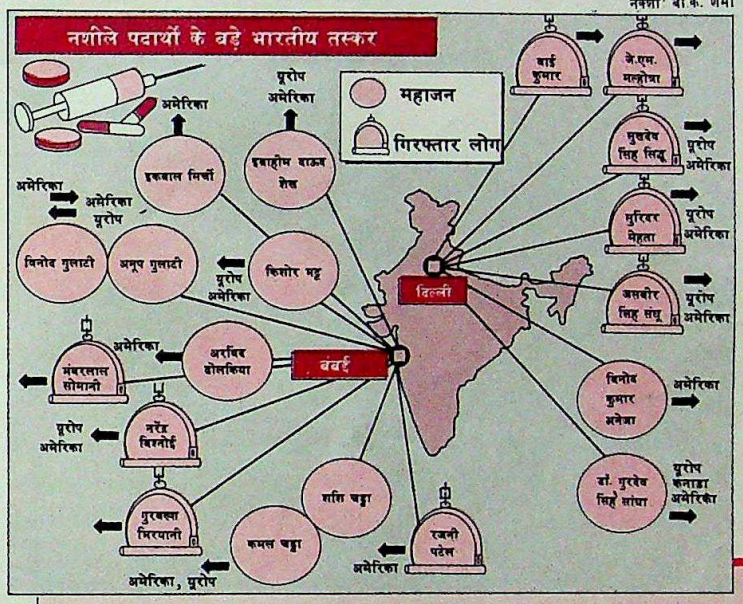

देश में सोने और नशीले पदार्थों की बरामदगी बढ़ी है. दोनों की तस्करी का रास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब व लंदन से होकर गुजरता है. कई अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसमें शामिल हैं

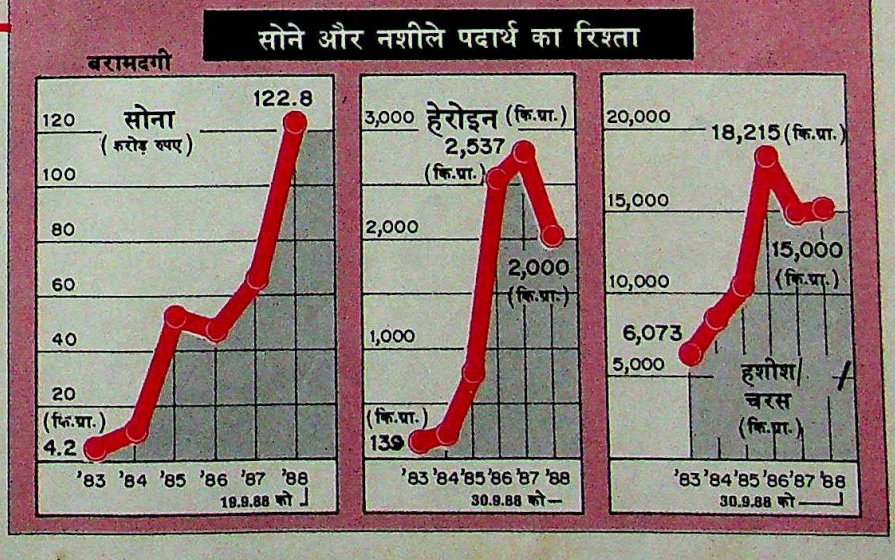

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमृतसर के तरनतारन के रहने वाले थे और पिछले कुछ वर्षों से सोने की तस्करी कर रहे थे. यह भी पता चला कि यह सोना दुबई से चला था.

सरकार के पास कई और सबूत हैं कि सोने की तस्करी के इस धंधे में अंतर-राष्ट्रीय अपराधी गिरोह शामिल हैं:—

▶ 1988 में जब्त की गई हशीश की सबसे बड़ी खेप 4,050 किलोग्राम की थी. यह ज्यूरिख भेजी जा रही थी जो सोने की खान माना जाता है. हालांकि जिस डिब्बे में यह हशीश बंद थी उस पर रॉटरडम का पता लिखा था मगर इसे पाने वाले के नाम में ज्यूरिख की एक कंपनी 'विलर्स इंपोर्ट' का.

▶ जनवरी में सीमा शुल्क अधिकारियों ने लुधियाना में एक ट्रक को रोककर 175 किलो हेरोइन और 39 किलो अफीम बरामद की. पैकेटों पर 'अशरक मशरक' और 'दोइयम' जैसे छापे लगे थे जिनसे उनके पश्चिम एशियाई संबंधों का संकेत मिलता है.

▶ एक महीने बाद 'राखुनि' के अधिकारियों ने दिल्ली में एक पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद दीन को गिरफ्तार किया और उसके पास से 110 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य के सोने के 279 बिस्कुट बरामद किए. माना जाता है कि कुछ दिन पहले ही सीमा पार कर भारत आया मुहम्मद दीन पश्चिम एशिया के एक बड़े तस्कर गिरोह का महत्वपूर्ण सदस्य था.

▶ फरवरी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नीरज सामधी को पकड़ा. दिल्ली में बसे इस अफगान शरणार्थी से 237 किलो हशीश बरामद हुई जिसे वह पश्चिमी देशों में भेजने की फिराक में था. दिल्ली तक यह खेप पंजाब सीमा पर सक्रिय वे लोग लाए थे जो नशीले पदार्थ इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं.

▶ मई में भारत-पाक सीमा के खेमकरण क्षेत्र में तस्करों के गिरोह और बीएसएफ जवानों के बीच गोलीबारी हुई. तस्कर तो किसी तरह भागने में कामयाब हो गए लेकिन वे 150 किलो हेरोइन छोड़ गए. यह किसी पश्चिम एशियाई देश से आ रही थी.

वैसे तो सोने के तस्करों के लिए नशीले पदार्थों की कमाई सबसे बड़ी पूंजी बन गई है, लेकिन वे दूसरे स्रोतों पर भी हाथ मारते रहते हैं. 'राखुनि' के अनुसार आप्रवासी भारतीय भी उनके एक स्रोत हैं. भारत सरकार के एक सूत्र के अनुसार सोने की तस्करी में पैसा लगाने के हवाला लेन-देन में 50 लाख रु. से भी ज्यादा की भारतीय मुद्रा खर्च की जाती है.

अधिकारियों ने आयात के बड़े बीजक बनाने के भी कई मामले पता लगाए हैं. इसके पीछे मकसद जरूरत से ज्यादा विदेशी मुद्रा हासिल करके उसे सोने की तस्करी में लगाना होता है. पिछले पांच महीनों में अधिकारियों ने कई ऐसे मामलों का पता लगाया है जिनमें किताब जैसी चीजों के आयात के लिए 10 करोड़ रु. से भी ज्यादा के अतिरिक्त बीजक बनाए गए. किताबें खुले लाइसेंस के तहत ही आयात की जा सकती हैं. फिलहाल, कला और शिक्षा विषयक किताबों के आयात के लिए किसी लाइसेंस या पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती. इसका फायदा उठाकर तस्कर ऐसी किताबें 'खरीदते' हैं जिन्हें विदेशी प्रकाशक मामूली कीमत पर ही दे देते हैं. फिर, वे 60-70 फीसदी तक मिलने वाली इस छूट को छिपाकर विदेशी मुद्रा के लिए रिजर्व बैंक को अर्जी दे देते हैं. इस पैसे को विदेशों में जमा करके हवाला लेन-देन किया जाता है और उससे हुई आमदनी सोने की तस्करी में लगा दी जाती है.

सोने की तस्करी की वजह से ढेर सारी विदेशी मुद्रा गैरकानूनी ढंग से बाहर चली जाती है. इससे देश में काले धन में भी इजाफा होता है. यही वजह है कि सोने के व्यापारी इसके आयात को और उदार बनाने के लिए दबाव डालते रहे हैं. नतीजा यह है कि सरकार ने नियम उदार कर दिए हैं. पर इस छोटी-मोटी छूट से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक सोने पर मिलने वाले 'अतिरिक्त' पैसे का अनुपात घटता नहीं, और उसकी तस्करी पर मुनाफा नहीं घटता. बहरहाल, इस शुभ घड़ी के आने तक सोना अपनी लुभावनी चमक से औरतों और तस्करों को मोहित करता ही रहेगा.

अपने दुबई के दफ्तर में दाऊद इब्राहीम

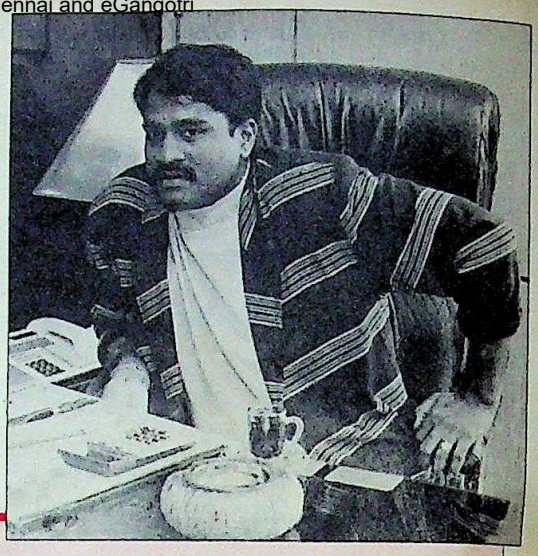

नशीले पदार्थों और सोने की तस्करी में दुनिया के सबसे ताकतवर और हिंसक अपराधी गिरोहों का बोलबाला है. दरअसल भारत अब पश्चिम को तस्करी से भेजे जाने वाले नशीले पदार्थों के लेन-देन का प्रमुख अड्डा बन चुका है

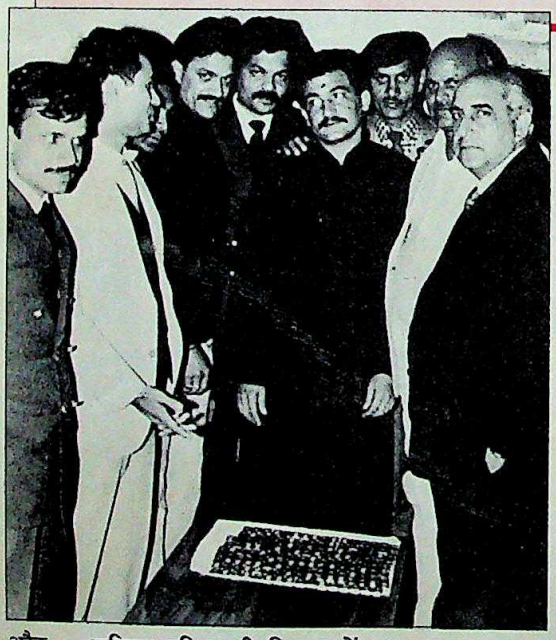

खुफिया पुलिस की गिरफ्त में एक तस्कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया ओनिडा.
इसे छू पाये तो बस एक ईर्षा भरी नज़र!

ईप्सा में जब भी ईर्षा के रंग घुल जाये, और हाथ अनजाने में ही पत्थर उठा ले, तब जानिये, फिर एक नया ओनिडा तशरीफ़ लाया होगा! बेशक़! नया ओनिडा हाज़िर है अपने अछूते 'क्यूब लुक' के साथ। अत्याधुनिक कारीगरी का जादू एक पूरी तरह से 'मोल्डेड' कैबिनेट और अनोखे काले ट्यूब में समाये हुये—मनमोहक रूप-रंग और आने वाले कल की अदा लिये—आ बसा है नया ओनिडा आप के इशारों के इन्तज़ार में!

लेकिन, पहले इसके कि आप इसमें बेखबर खो जायें, भूलिये मत कि ईर्षा मंडराती है आसपास। याद रखिये वो सावधान-वाणी: अपने पड़ोसियोंसे नाता ज़रूर जोड़िये, पर अपने ओनिडा को अकेला मत छोड़िये।

ओनिडा. पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्र. क्या बेटे के लिए खिलौना लाए हैं ?

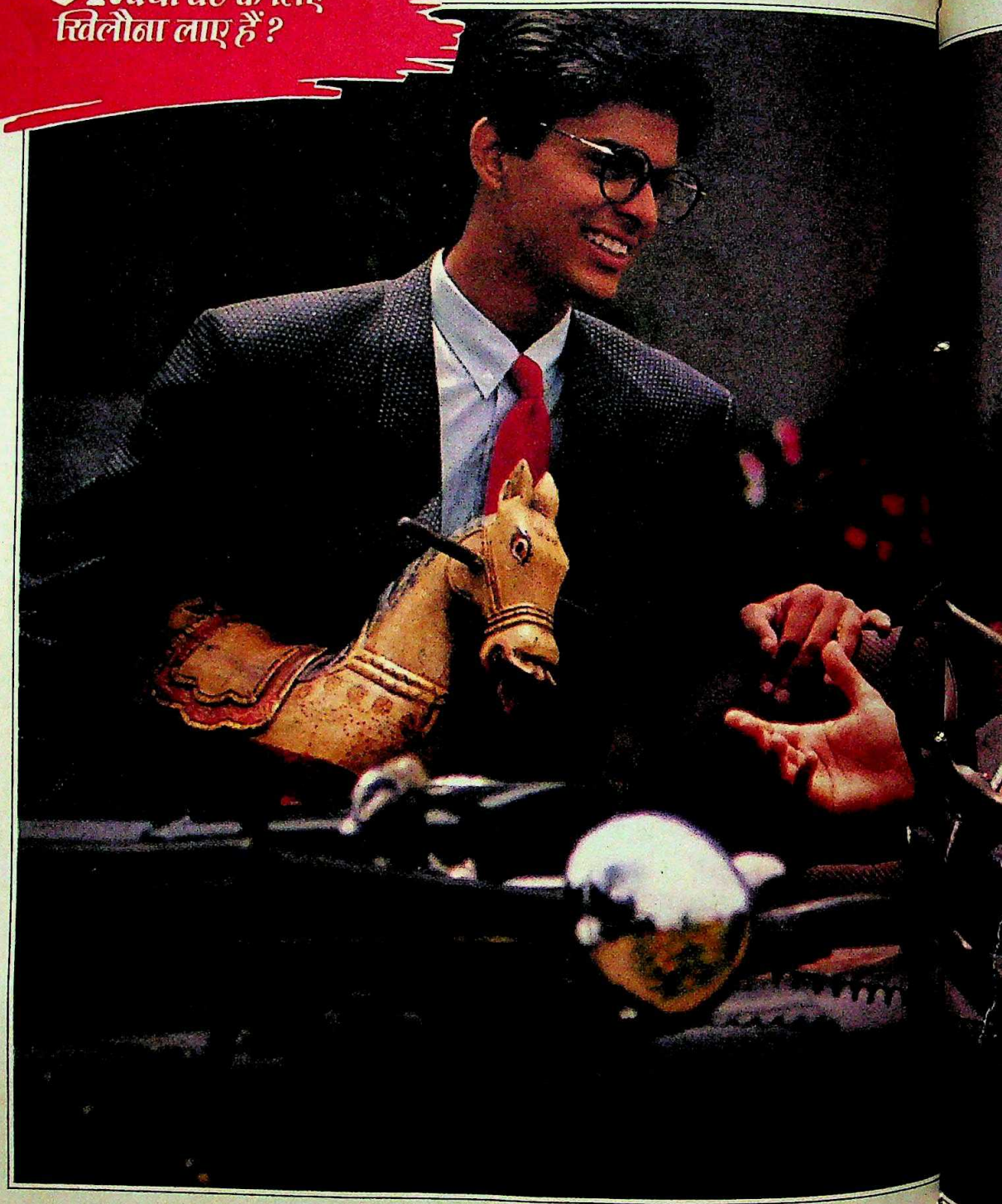

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रे म ण्ड स फ़ा य र

उ. नहीं अपने लिए,
साहेबजादे तो
अब कंप्यूटर से खेलते हैं!

रेमण्ड
सर्वांगीण सर्वोत्तम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रानूट्रोल हंसा एक्वा मिक्सर. मनचाहा गर्म, गुनगुना या ठंडा पानी पाने का सरलतम तरीका.

और रानूट्रोल हंसा एक्वा मिक्सर में यह सब संभव है केवल एक लीवर से — जिसे घुमाने भर से मिले मनलायक ठंडा या गरम पानी — आप बस गुनगुनाते रहें रानूट्रोल हंसा के गुण। इसी लीवर को ऊपर करते ही आप जितनी चाहें पानी की उतनी तेज़ धार और नीचे दबाने पर धीमी-धीमी धार। है न सरल तरीका।

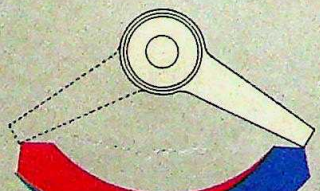

यह कमाल है विश्व में एक्वा मिक्सर के सबसे बड़े विक्रेता, हंसा मैटलवर्क ए.जी. की 'सिरामिक कारट्रिज' तकनीक का।

आप भी अपने बाथरुम में नहाने गुनगुनाने का मज़ा लेना चाहते हैं या किचन में मनचाहे पानी की सुविधा तो चुनिये आकर्षक डिज़ाईनों में से, अपना मनपसन्द रानूट्रोल हंसा।

RANUTROL HANSA
AQUA MIXER
From Hansa Metallwerke AG, West Germany.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कंपनियों पर कड़ी नजर

अपने अंशधारकों की सालाना बैठकों के समय अध्यक्षीय भाषणों को अखबारों में विज्ञापित करने वाली कंपनियां सावधान! टैक्स वाले इन्हीं भाषणों के आधार पर उनकी समृद्धि और उनके द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की जानकारी लेते हैं. इससे कंपनी द्वारा किए गए उत्पाद कर और आयकर के भुगतान का मिलान किया जाता है. वित्त मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि लाभांश तो कंपनी अपने बचत खाते से भी दे सकती है लेकिन जो कंपनियां अधिक लाभांश देने पर भी कम करों का भुगतान करती हैं वे संदिग्ध हो जाती हैं. वित्त मंत्रालय ने ऐसी 50 कंपनियों के नाम अपने कंप्यूटर में भर रखे हैं.

डिब्बाबंद कमाई

डिब्बाबंद चाय के निर्यात को बढ़ावा देने की सरकारी नीति अब रंग ला रही है. इसके तहत भारतीय चाय उद्योग के लोग विदेशों में अपने माल की बिक्री के लिए अनेक गठबंधनों की कोशिश कर रहे हैं. कई कंपनियों ने विदेशों की सुपर मार्केट शृंखला के जरिये अपना माल बेचने का करार भी कर लिया है. डंकन ने हॉलैंड की बारेंड्स के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय चाय व्यापार निगम ने ब्रिटेन की मार्क ऐंड स्पेंसर से और टाटा टी ने पश्चिम यूरोप की माराडून शृंखला की दुकानों के साथ डिब्बाबंद भारतीय चाय बेचने के ऐसे करार किए हैं. डिब्बाबंद चाय को दुनिया भर में बेचने के मामले में तेजी आने के पीछे सरकारी सोच यह है कि खुली चाय की तुलना में डिब्बाबंद चाय के निर्यात से ज्यादा कमाई होती है.

नए धंधे की इजाजत

सरकार ने इंडियन टुबैको कंपनी को संकर बीज के कारोबार में उतरने की अनुमति दे दी है. कंपनी ने प्रति वर्ष 10,000 टन बीज तैयार करने के लिए अमेरिका की नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ गठबंधन किया है. इस बीच, इस सिगरेट कंपनी के खाद्य तेल व्यवसाय की योजना में देरी हो रही है. सरकार ने उसे सूर्यमुखी और कपास जैसे बीजों से तेल निकालने की अनुमति तो दे दी लेकिन इसे परिष्कृत करने की नहीं. इसलिए अब कंपनी ने सरकार से उसके परिष्करण की अनुमति भी मांगी है.

हरियाली का रास्ता

रासायनिक खाद बनाने वाली जुआरी एग्रो केमिकल्स अब संसाधित सब्जियों का निर्यात करेगी. कृष्ण कुमार बिड़ला की यह कंपनी टमाटर, कुकुरमुत्ता, बांस की कोंपलों और मटर को संसाधित करने और इन्हें अमेरिका भेजने के लिए अमेरिकी खाद्य कंपनियों केलोग्स और पिल्सबरी फूड्स के साथ गठबंधन की बात चला रही है. दरअसल इसने पिल्सबरी के साथ सशर्त करार कर भी लिया है. और कुछ हफ्तों में ही अंतिम गठबंधन हो जाने की उम्मीद है. वैसे हो सकता है कि इस बीच किसी दूसरी कंपनी से ही गठबंधन हो जाए. हिमाचल प्रदेश में लगने वाली इस परियोजना पर 12 करोड़ रु. खर्च होंगे. जुआरी शुरू में खुद ही सब्जियां उगाएगी. लेकिन बाद में सब्जी उगाने वालों का समूह तैयार करेगी. इस बीच, कंपनी राजस्थान में 180 करोड़ रु. की लागत से सीमेंट का कारखाना लगाने के शुरुआती काम में लगी है. इसके लिए अनुमति पत्र उसे मिल चुका है. जमीन ली जा रही है और तकनीकी जानकारी के लिए बातचीत चल रही है.

रेल से मिले रोजगार

भारतीय रेल का अपने कर्मचारियों पर कुछ साल से बढ़ता जा रहा खर्च (देखें चार्ट) अगर कोई संकेत देता है तो यही कि रेलवे के 16 लाख कर्मचारियों के लिए इससे बढ़िया स्थिति पहले कभी नहीं रही. पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का दसवां हिस्सा रेलवे में ही काम करता है. 1982-83 से 1986-87 के बीच के पांच वर्षों में प्रति कर्मचारी रेलवे

चार्ट: बी.के. शर्मा

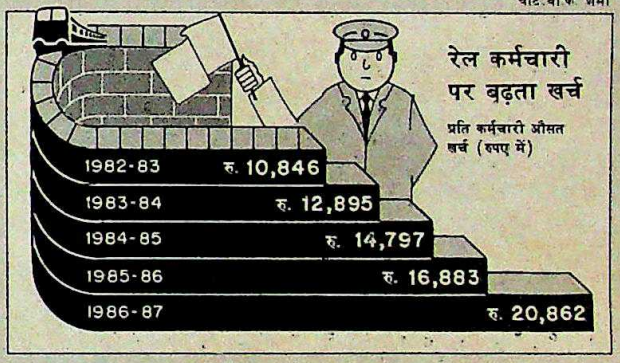

का औसत खर्च दुगुना हो गया है (10,846 रु. से बढ़कर 20,862 रु.). यानी 1986-87 में औसत भारतीय परिवार की तुलना में रेलवे कर्मचारियों की आय दुगुनी से अधिक थी. लेकिन बैंक कर्मचारियों की स्थिति इससे भी बेहतर है. बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की 1986 में औसत आय 30,858 रु. थी.

पर्यटन से भोजन

भारतीय पर्यटन विकास निगम तैयार भोजन के व्यवसाय में भी उतर रहा है. इस सरकारी होटल कंपनी ने वैष्णो देवी और मसूरी में ऐसे भोजन की दुकानें खोल भी दी हैं. जल्दी ही कटरा, हरिद्वार और बनारस में ऐसी दुकानें खुलेंगी जिनमें निगम के साथ निजी होटलों और राज्य सरकारों की साझेदारी रहेगी. बनारस वाली दुकान में उत्तर प्रदेश सरकार के 51 फीसदी शेयर होंगे. निगम अब कुछ आप्रवासी भारतीयों के साथ गठबंधन करके महानगरों में भी ऐसी दुकानें खोलने की संभावनाएं तलाश रहा है. उसके पास अनेक आप्रवासी भारतीयों के प्रस्ताव पड़े भी हैं. विदेशों में भी ऐसी दुकानें खोलने की योजना है. पर यह बहुत दूर की बात है. तैयार भोजन को कभी बड़ी तेजी से बढ़ने वाला धंधा माना जाता था लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं (जैसे यूनाइटेड ब्रुअरीज के पिजा किंग) की नाकामी के बाद इधर आने का शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ गया है. लेकिन निगम को उम्मीद है कि छोटे शहरों में उसका यह कारोबार जरूर चमकेगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आठवीं योजना

चादर भर पांव फैलाने की बात

खर्च के मामले में कठोर संयम बरतने के योजना आयोग के सुझाव

खर्च के मामले में कठोर संयम की जरूरत होनें के बावजूद देश और सरकार दोनों ही खुले हाथ से पैसा लुटाते जा रहे हैं और चादर के बाहर पांव फैला चुके हैं. इसका एहसास अधिकांश अर्थशास्त्रियों को भी है. लेकिन नई बात यह है कि इस बार देश के योजनाकारों ने भी आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तय करते समय यह चिंता जाहिर की है. इन योजनाकारों ने सरकार से मांग की है कि वह:

► कर के आधार को व्यापक बनाकर अधिक राजस्व की व्यवस्था करे. उद्योगों को दी जा रही कुछ रियायतों को वापस लेकर यह किया जा सकता है.

► खर्च कम करे. लगातार घाटा दे रही सरकारी कंपनियों को बंद करना या निजी कंपनियों के साथ जोड़ देना होगा.

► अनुदान कम करे. जैसे रासायनिक खादों पर दिए जाने वाले अनुदान को कम करने के लिए सरकार दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू कर सकती है. मिलों को अपना 25 फीसदी उत्पादन खुले बाजार में बेचने की इजाजत दी जा सकती है ताकि वे नियंत्रित मूल्य पर माल बेचने से हुआ घाटा कुछ हद तक पूरा कर सकें.

► मौजूदा संरचनात्मक संसाधनों का अधिक अच्छा उपयोग करे और मोटी पूंजी खपाने वाली नई योजनाएं न शुरू करे.

► विदेशी निवेश के माहौल बनाए.

► निर्यात को दोगुना करे.

► उपभोग कम कराके और प्रोत्साहन देकर बचत दर को बढ़ाए. (करदाताओं के लिए अनिवार्य जमा योजना लागू करने का सुझाव पहले ही दिया जा चुका है).

इतना ही काफी नहीं होगा. योजना आयोग योजना के काम को विकेंद्रित करने की बात भी सोच रहा है. अभी देश के पांच मॉडल जिलों में अलग से योजना बनाने का प्रयोग होगा. अगर आयोग की चली, तो सरकार अपने कई काम निजी क्षेत्र के हवाले कर देगी और आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप कम होता जाएगा. योजना आयोग के सदस्य राजा चेल्लिया कहते हैं, "मेरा मानना है कि सरकार को कई क्षेत्रों से बाहर निकल जाना चाहिए और आर्थिक पाबंदियों को कम-से-कम कर देना चाहिए.

योजना आयोग के दूसरे लोग भी यही सब कुछ कहते हैं. सदस्य आबिद हुसैन कहते हैं, "राज्य का हस्तक्षेप तो रहेगा लेकिन इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा. और यह हस्तक्षेप आर्थिक मामलों की जगह सामाजिक मामलों में होगा."

इनमें से कुछेक बातें आठवीं योजना में जगह पा सकती हैं या नहीं भी पा सकती हैं. अब से कुछ महीनों के अंदर ही यह अंतिम रूप ले लेगा. तब यह पता चल जाएगा. इसी पखवाड़े के आखिर में राजीव गांधी और उनके कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आयोग के सदस्यों की जो बैठक होनी है उसमें भी कुछ कड़े उपायों पर विचार किया जाना है.

लेकिन आर्थिक कड़ाई की बातें उन लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी जिनकी नजर मतपेटियों पर है. अपना नाम नहीं प्रकट करना चाहने वाले एक मंत्री ने कहा, "चुनाव के करीब होने के कारण इन कठोर उपायों पर अमल की कोई संभावना नहीं है. अगले साल नई सरकार के गठन के बाद ही इन उपायों पर अमल हो पाएगा."

लेकिन सुधार की जरूरत पर बहुत कम लोग ही आपत्ति करेंगे. खतरनाक बात यह है कि सरकार जितना पाती है उससे कहीं ज्यादा खर्च करती है, और उधार के पैसे से काम चला रही है. 1981-82 और 1986-87 के बीच के छह वर्षों में सरकारी आय 17.2 फीसदी की औसत दर से बढ़ी. लेकिन खर्च 18.3 फीसदी तक बढ़ गया. आमदनी और खर्च का जो मौजूदा स्तर है उसके कारण पांच वर्ष बाद आमदनी और खर्च का अंतर बढ़कर 50,000 करोड़ रु. हो जाएगा.

इससे भी बुरी बात यह कि सरकारी आमदनी का ज्यादातर भाग प्रशासनिक और गैर-विकास मदों में खर्च होता है. आठवीं योजना के प्रारंभिक दस्तावेज पर योजना आयोग की टिप्पणियों के मुताबिक, इस दशक के प्रथम छह वर्षों में सरकारी क्षेत्र में वेतन का बिल दोगुना हो गया. और यह सिर्फ महंगाई के कारण नहीं हुआ है. यदि वेतन और महंगाई में संतुलन होता और यदि कर्मचारियों की कुल संख्या स्थिर रहती तो वेतन के मद में आज 4,500 करोड़ रुपए से भी कम खर्च होते.

सरकार अपने राजस्व का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा रियायतों, ब्याज अदायगी और रक्षा के मदों में खर्च करती है, जिससे समस्या और भी जटिल हो गई है. इसका नतीजा यह निकला कि उसने योजनाओं में पैसा लगाने के लिए कर्ज लिया. (सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में 96 फीसदी निवेशों में कर्ज का धन लगाया गया था). कुल मिलाकर इन सबने देश को गिरवी रख दिया है. 1980-81 में केंद्र की देनदारी 59,749 करोड़ रुपए थी जो 1986-87 के साल में 179 फीसदी बढ़कर 1,66,546 करोड़ रुपए हो गई.

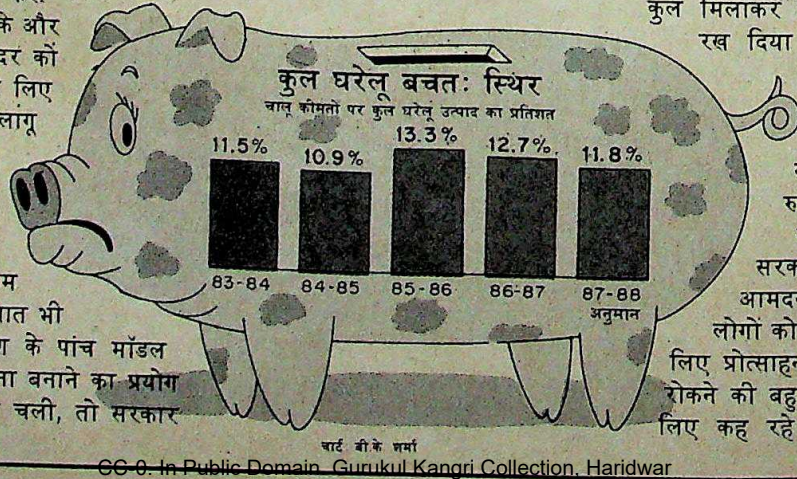

चार्ट: बी.के. शर्मा

यही वजह है कि योजनाकार सरकार से खर्च में कटौती करने, आमदनी बढ़ाने, कंपनियों और लोगों को और ज्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहन देने और फिजूलखर्ची को रोकने की बहुआयामी रणनीति बनाने के लिए कह रहे हैं. वे संपत्ति के अधिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

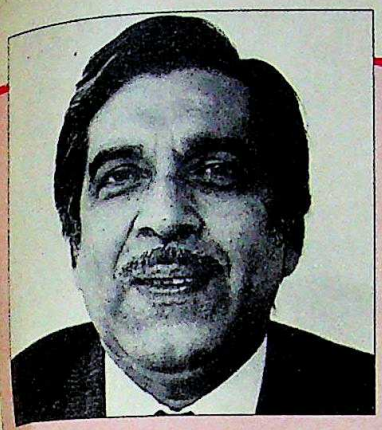

"आठवीं योजना अर्थव्यवस्था में ऊर्जा भरने के उपाय करने जा रही है"

वाई. के. अलघ
सदस्य, योजना आयोग

"सरकार को आर्थिक पाबंदियां कम-से-कम कर देनी चाहिए"

राजा चेल्लिया
सदस्य, योजना अयोग

"राज्य का हस्तक्षेप तो रहेगा ही लेकिन सामाजिक मामलों में"

आबिद हुसैन
सदस्य, योजना आयोग

कुशलता से इस्तेमाल के उपाय भी बता रहे हैं. दरअसल, योजना आयोग के सदस्य वाई.के. अलघ इसे आठवीं योजना की अति महत्वपूर्ण बातों में एक मानते हैं. वे कहते हैं, "आठवीं योजना अर्थव्यवस्था में ऊर्जा भरने के उपाय करने जा रही है. लक्ष्य उत्पादन के नहीं बल्कि कार्यकुशलता के तय किए जाएंगे. और यहीं पर आठवीं योजना सातवीं योजना से भिन्न होगी."

यदि कार्यकुशलता एक मंत्र है तो नवीकरण और आधुनिकीकरण दूसरे मंत्र हैं. सड़कों का हवाला देते हुए एक अधिकारी कहते हैं कि 10 में से एक राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यापक मरम्मत की जरूरत है. कुछ बिजली घरों को तो बदल ही देना होगा.

सरकार बहुत दूर की सोच रही है. वह वार्षिक विकास दर का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना चाहती है. यह लक्ष्य पिछले पखवाड़े की बैठक में तय होना था, लेकिन आम राय यह थी कि 6 फीसदी विकास दर का लक्ष्य ठीक रहेगा. विकास की यह दर सातवीं योजना से एक फीसदी ज्यादा है.

दर चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि उच्च विकास दर के लिए भारी निवेश जरूरी है. नकद रकम जुटाने का एक तरीका यह है कि बचत की पहले से ही ऊंची कुल दर बढ़ाई जाए. यह दर फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद की 21 फीसदी है. क्या यह किया जा सकता है? इस दर में 1 फीसदी की वृद्धि से भी बचत में लगभग 3,000 करोड़ रु. की वृद्धि हो जाएगी. योजना आयोग का विश्वास है कि यह संभव है, बशर्ते सरकार आमदनी और खर्च में संतुलन रखे. दरअसल, सरकार की फिजूलखर्ची ही बचत दर को नहीं बढ़ने दे रही है. फिजूलखर्ची रोक देने से यह दर 23 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

लेकिन तर्क तो तर्क ही हैं. सरकारी खर्चे पर रोक लगाने की बात करना आसान है, रोक लगाना नहीं. एक अर्थशास्त्री रूखेपन से कहते हैं, "क्या आप सरकारी कर्मचारियों को इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वे अपने वेतन में बढ़ोतरी पर रोक को स्वीकार करें?" घरेलू बचत भी स्थिर हो गई है (चार्ट देखें). कुछ अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि लोग अपना खर्च बढ़ाते ही जा रहे हैं. यदि यह सच है तो संसाधनों को जुटाना और भी ज्यादा कठिन होगा.

आमदनी के मामले में उम्मीद इसलिए बंधती है क्योंकि सरकार अंततः कर के जाल को और फैला रही है. राजस्व राज्यमंत्री अजीत पांजा कहते हैं, "हम कर के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं. पहले हमारी नजर निजी सेवाओं पर है. मसलन नाइयों का धंधा खूब चल पड़ा है पर इनमें कोई कर अदा नहीं करता." अगले कुछ महीनों में सरकार अछूते छोटे धंधों को टटोलने का भी एक प्रयोग चलाएगी. डॉक्टरों, वकीलों और ऐसे ही दूसरे पेशेवालों को जवाबी पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे जिनमें उनसे अपनी आय का ब्यौरा भरकर भेजने को कहा जाएगा. जो जवाब नहीं देंगे, उनके घर कर अधिकारी पहुंच जाएंगे. यदि इससे आमदनी बढ़ती है तब इसे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा.

इस बीच योजनाकारों की कई मान्यताओं की आलोचना भी होने लगी है. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एस. भल्ला निजी क्षेत्र के प्रति इस नए रुझान के आलोचक हैं. वे कहते हैं, "सरकारी बयानों में इस पर जोर दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र निकम्मा है और निजी क्षेत्र कार्यकुशल है. लेकिन निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता उन लोगों की अनदेखी करता है जिनके पास धन नहीं है. यह भारत के बारे में अनभिज्ञता उजागर करता है."

इसमें भी संदेह है कि रियायतों में कटौती का कोई राजनैतिक परिणाम नहीं होगा. एक सरकारी अधिकारी पूछते हैं, "किसानों को सिंचाई के लिए पानी रियायती दर पर मिलता है. क्या आप वाकई सिंचाई की दरों को बढ़ा सकते हैं?" कृषि मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष भल्ला फौरन कहते हैं कि रासायनिक खाद पर रियायतों में कटौती का मतलब किसानों का शोषण होगा. वे कहते हैं, "अनाज की मांग में सालाना 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी. वास्तविक तौर पर भारतीय किसानों को रासायनिक खाद की कीमत दक्षिण एशिया के किसानों से अधिक देनी पड़ती है. आप कीमत और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते."

यह सही है कि पहले की कई योजनाओं ने सरकार को कर का दायरा बढ़ाने और योजना के विकेंद्रीकरण की तरफ प्रेरित किया है. और कई राज्यों में तो राज्य और जिला योजना बोर्ड भी हैं. लेकिन वित्तीय अधिकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फ़ोटोग्राफ़ी से पहली मुलाकात, सौ साल पहले.

लाला दीनदयाल, हैदराबाद के एल्बम से: सौ साल से भी अधिक पुरानी तस्वीर.

अपने पारिवारिक एल्बम के कुछ पन्ने पलटाकर देखिए, जिनमें सजी हैं बरसों पुरानी यादों को संजोए चंद तस्वीरें!

ब्लैक एंड व्हाइट में साठ, सत्तर या सौ साल बाद भी उतनी ही साफ़, स्पष्ट और ज्यों की त्यों.

इसलिए जब भी आप किसी नाज़ुक लम्हे की मीठी याद कैमरे में क़ैद करना चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म ही इस्तेमाल करें. जिन्हें एक बार खींच कर आप बरसों नाज़ करेंगे.

वक़्त, यादों को भले ही धुंधला दे....
पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें कभी धुंधली नहीं होतीं.

इन्दु ब्लैक एंड व्हाइट रोल फ़िल्म और ब्रोमाइड पेपर.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
Gurukul Kangri Collection, Haridwar
Sista's – HPF:956.88 HIN A

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न होने के कारण ये संस्थाएं बूढ़े शेर की तरह ही हैं, जो कुछ नहीं कर पाते.

कम-से-कम यह हालत तो बदली जा सकती है. कुछ महीने पहले एक सरकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें सिफारिश की गई है कि योजना प्रक्रिया में जिलों को सम्मानजनक स्थान दिया जाए और उन्हें अलग बजट बनाने का अधिकार दिया जाए. इसका मतलब यह है कि राज्यों को अपना बजट बांटना होगा. इस मुद्दे पर केंद्र की राज्यों के साथ दो बैठकें हुईं पर प्रतिक्रिया मिश्रित ही रही. अलघ कहते हैं, "मुझे शक ही है कि कुछ संसाधनों पर जिलों का नियंत्रण हो पाएगा."

बहरहाल, योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन की एक कोशिश चल रही है. पहले होता यह रहा है कि सरकारी विभाग कार्यदलों का गठन किया करते थे जो अधिक पैसे की मांग पेश करते. एक अधिकारी कहते हैं, "यह खरीद-फरोख्त की सूची जैसी होती थी. पिछली योजना में कुल विभागीय खर्च 3,20,000 करोड़ रु. का था. यह रकम वास्तविक योजना रकम की ठीक दोगुना है." इसके बाद कार्यदलों ने योजना आयोग के विभागों के पास दरख्वास्त की. इन विभागों ने उनके इस दरख्वास्त की जांच-पड़ताल के बाद उनकी मांगों को आधा कर दिया. अंत में योजना आयोग के सदस्यों ने आखिरी रिपोर्ट देखी. अब वे इस पूरे मामले पर शुरू से नजर दौड़ा रहे हैं क्योंकि वे उन तथाकथित संचालक दलों के अगुआ हैं जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और रणनीति पर विचार-विमर्श करते हैं. एक सदस्य ने कहा, "इस तरीके से हम बहानों के बदले अधिक ठोस योजना बना सकेंगे."

जगन्नाथ नेगी

"हम कर का दायरा बढ़ाना चाहते हैं. हमारी नजर निजी सेवाओं पर है"

अजीत पांजा
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री

लेकिन दिल्ली अभी दूर है. किसी योजना की नियति योजनाकारों के नहीं राजनीतिकों के हाथ में होती है. आमूल परिवर्तन के लिए राजनैतिक संकल्प शक्ति उन्हें ही दिखानी होगी. लेकिन फिलहाल तो ऐसी संकल्प शक्ति का कोई भी संकेत नहीं दिखता. **—पलकुन्नयु जी. मथाई**

500 रु. के नोट

धंधेबाजों की चांदी

पांच सौ रुपए के नोट की कीमत क्या है? जाहिर है, आप कहेंगे 500 रु. इसका जवाब हां है और न भी. नोट का अंकित मूल्य तो इतना ही है. लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के परिसर में ही आप इसे 510 रु. में बदल सकते हैं और मांग ज्यादा हो तो 515 रु. में भी 'बेच' सकते हैं. इन नोटों को चाहने वाले इन पर तेजी से झपट्टा मारते हैं.

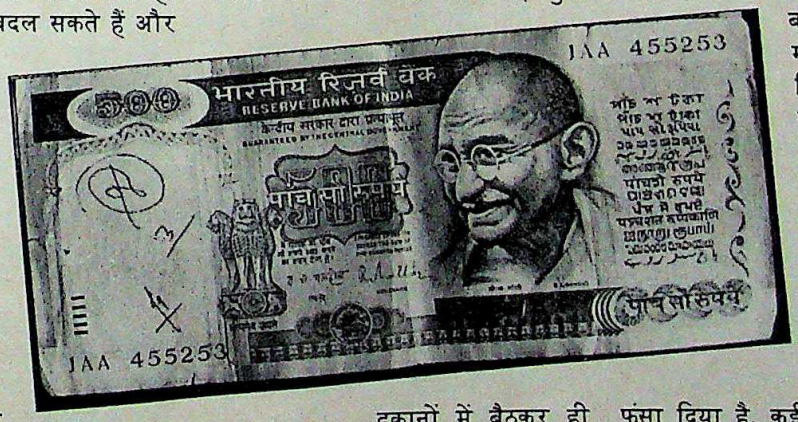

500 रु. के पूरे 50 लाख नोट साल भर पहले जारी किए गए थे. नोट दो एक-दम भिन्न कारणों से प्रचलन से बाहर हो गए हैं: एक तो कालाबाजारी करने वालों और तस्करों की मांग से, दूसरे, नोट छापने वाले सरकारी छापाखाने में श्रमिक समस्या की वजह से. पिछले महीने रिजर्व बैंक की दिल्ली शाखा का 500 रु. के नोट वाला काउंटर बंद कर देना पड़ा.

जब काउंटर खुला था उस वक्त भी एक व्यक्ति को एक बार में केवल एक नोट दिया जाता था. लेकिन नोटों का जुगाड़ करने वालों ने कई जुगतें भिड़ा रखी थीं. धंधा करने वालों के आदमी दिन भर कई-कई मर्तबा लाइन में लगते थे. धंधेबाजों ने बताया कि बैंक के बाबुओं से उनकी सांठगांठ रहती थी.

इस धंधे के धुरंधर तो दिल्ली की संकरी गलियों में स्थित अपनी दड़बेनुमा दुकानों में बैठकर ही कामकाज चलाते हैं. स्थानीय छोटे धंधे-बाज इन दुकानों पर बड़े नोट बेचने आते हैं. इनके ग्राहक या तो काला धन जमा करने वाले हैं या फिर तस्कर. धंधे में लगे दिल्ली के खलीफा पंजाब सीमा पार के तस्करों को नोट उपलब्ध कराते हैं जबकि बंबई के धंधेबाजों का बाजार खाड़ी और उससे पार तक फैला हुआ है.

दुबई और सिंगापुर सरीखी जगहों से खरीदारी करने वालों के बीच भी 500 रु. के नोटों की बड़ी मांग है. इन जगहों के दुकानंदारों ने हाल में भारतीय रुपए को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है. बाहर जाने वाले लोगों के लिए बड़े नोट काफी सुविधाजनक हैं.

सरकार को सारी बातों की खबर है. मध्य प्रदेश की देवास स्थित टकसाल में छपे सभी 5 करोड़ नोट जारी कर दिए जाएं तो इनकी मांग काफी हद तक पूरी की जा सकती है. लेकिन कुछ इंका सांसदों की अगुआई वाले श्रमिक संघ ने इसमें फच्चर फंसा दिया है. कई महीनों से समझौता वार्ताएं चल रही हैं लेकिन फिलहाल गतिरोध जारी है.

कर्मचारी और सरकार दोनों ही इन हालात से चाहे जितने दुखी हों लेकिन धंधेबाज खुश हैं क्योंकि वे चांदी काट रहे हैं. वे जरूर गतिरोध जारी रहने की दुआ करते होंगे. **—डेविड देवदास**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

उद्यम की चमक

टॉर्च बनाने में कुक्शी कस्बा आगे

दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले धार का कुक्शी कस्बा (आबादी: 20,000) उन छोटे कस्बों में से ही एक माना जाएगा जो अपने आसपास की ग्रामीण जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए बस जाते हैं. यातायात व संचार सुविधाएं भी यहां नाम की ही हैं. पहाड़ियों से गुजरती संकरी-सी धूल भरी सड़क ही इसे बाकी दुनिया से जोड़ती है. भीलों के लुटेरे गिरोहों के कारण शाम ढलते ही यह सड़क सूनी भी हो जाती है.

लेकिन तमाम विसंगतियों के बावजूद कुक्शी में रिचार्जेबल फ्लैश लाइट्स (छोटी टॉर्चों) का उद्योग तेजी से पनप रहा है. पिछले पांच वर्षों में यहां टॉर्चों और उसके पुर्जे तैयार करने वाली तकरीबन 24 इकाइयां शुरू हो गई हैं. घरों के पिछवाड़े ही चलने वाली ये इकाइयां हर साल तकरीबन एक लाख टॉर्च तैयार करती हैं. 1.50 करोड़ रु. की सालाना बिक्री वाले इस उद्योग से लगभग एक हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है.

फिर से चार्ज होने वाली टॉर्च इस देश में नई हैं. सूखी बैटरियों की बढ़ती कीमतों के कारण इन टॉर्चों में वे एक्युमुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं जो फोटोग्राफरों के फ्लैशगन में लगते हैं. ये एक्युमुलेटर फिर से बिजली द्वारा चार्ज किए जा सकते हैं. पखवाड़े में एक बार इस बैटरी को कुछ घंटों के लिए बिजली से जोड़ देना होता है. बैटरी में आसवित जल डालते रहना जरूरी है.

मूलतः किसानों के लिए तैयार की गई इन टॉर्चों में एक सॉकेट लगा होता है, जिससे ट्रांजिस्टर, टेप-रिकार्डर और छोटे टीवी सेट चलाए जा सकते हैं. मॉडल के अनुसार 150 रु. से 200 रु. में मिलने वाली ये टॉर्चें पांच साल तक चलती हैं.

इस टॉर्च का पहला नमूना धार जिले के एक खोजी किसान लखनलाल कुमावत ने दस साल पहले तैयार किया था. तब वे केवल 23 वर्ष के थे. अपने दोस्त लक्ष्मी नारायण काग के साथ उन्होंने इस पर काम शुरू किया था. उन्होंने एक फोटोग्राफर से चार वोल्ट का एक एक्युमुलेटर उधार लिया और टीन के डिब्बे में पहली टॉर्च तैयार की. उनके रिश्तेदारों और मित्रों के बीच यह टॉर्च इतनी पसंद की गई कि इन्हें बड़े पैमाने पर तैयार करने का रास्ता खुल गया.

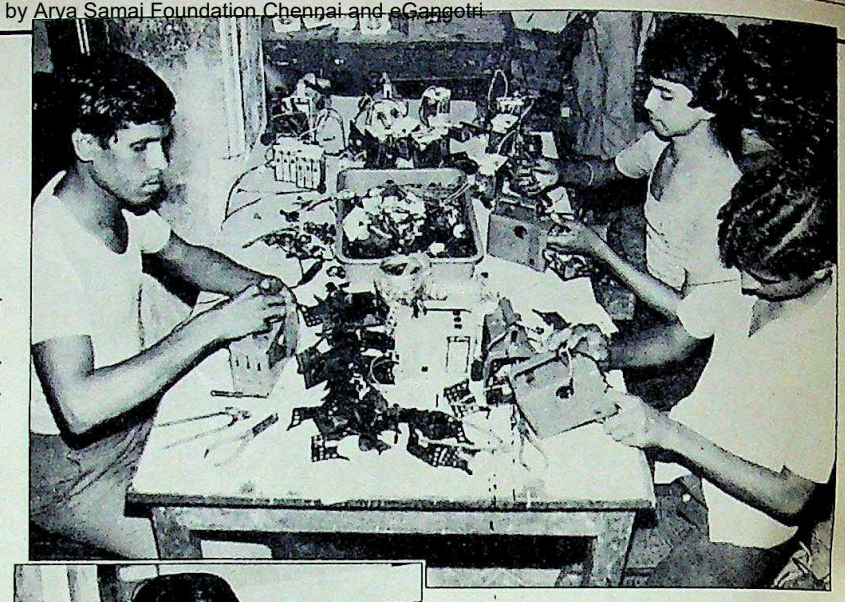

कुक्शी के एक टॉर्च कारखाने में कार्यरत मजदूर; और (बाएं) लखनलाल कुमावतः कामयाबी

लेकिन शुरू के कड़वे अनुभवों को याद करते हुए कुमावत कहते हैं, "यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ." धार के जिला उद्योग केंद्र ने बैंक से कर्ज की उनकी अर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिख दी. लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के एक उत्साही अधिकारी ने उद्योग विभाग के निर्णय को नकारते हुए इन युवा उद्यमियों को 55,000 रु. का कर्ज दिला दिया. इसका अच्छा नतीजा निकला. 1981 में पहली रिचार्जेबल टॉर्च 'किसान सेविका' अस्तित्व में आई.

बाद में इस टॉर्च में छह वोल्ट के एक्युमुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी रोशनी तेज की गई. धीरे-धीरे इंदौर में भी कई लोगों ने इसका निर्माण शुरू कर दिया. लेकिन कुक्शी आज भी इस उद्योग का गढ़ बना हुआ है.

इन लघु इकाइयों को एक लाख रुपए से भी कम की पूंजी से शुरू किया जा सकता है. एक इकाई 20 से 30 लोगों को रोजगार दे सकती है. इस उद्योग ने इस पिछड़े क्षेत्र का कायापलट कर दिया है. मिसाल के तौर पर पहले यहां इक्का-दुक्का बसें ही नजर आती थीं लेकिन अब दूसरे शहरों को माल पहुंचाने के लिए भाड़े की आधा दर्जन टैक्सियां दौड़ती रहती हैं.

इस समय इस उद्योग की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मुहैया कराया जाए जिसकी बराबर कमी बनी रहती है. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण धार में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर से मुक्ति और 25 फीसदी पूंजीगत अनुदान मिलता है. लेकिन ये सुविधाएं इकाई के पंजीकरण के बाद ही मिलती हैं. ऐसी ही एक इकाई के मालिक कहते हैं, "राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारी पंजीकरण के लिए रिश्वत की मांग करते हैं."

लेकिन नौकरशाही लोगों के उद्यम के उत्साह को मंदा करने में सफल नहीं रही है. खारगांव जिले के बरवानी में एक छोटे-से घर में कुमावत आज भी तरह-तरह के प्रयोग करते रहते हैं. वे 12 वोल्ट की टॉर्च का नमूना विकसित कर चुके हैं, और अब वे सौर ऊर्जा से चलने वाली टॉर्च लाइट का नमूना बनाने में जुटे हैं. जो हो, कुक्शी के इन युवा उद्यमियों ने यह तो साबित कर ही दिया है कि उद्यमशीलता बड़े शहरों की ही बपौती नहीं है.

—नरेंद्र कुमार सिंह, कुक्शी और बरवानी में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीटीसी

कई सवालों की जद में

सरकार ने अंततः हाथ डालने का फैसला किया

इस मामले में जासूसी फिल्मों जैसे सभी लटके-झटके हैं. उत्पादकर और आयकर विभाग के गुप्तचर देश भर में सबूत जुटाने के लिए दौड़भाग करते हैं. कंपनी के बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है. अदालती मामले चलते हैं. एक कर अधिकारी पर बलात्कार की कोशिश का आरोप भी लगता है. कर अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं या उनसे अपनी जांच रोक देने के लिए कहा जाता है.

इस सबके बावजूद छह महीने तक हां-ना के ऊहापोह में पड़े रहने के बाद सरकार ने आखिर जीटीसी इंडस्ट्रीज पर हाथ डालने का फैसला कर ही लिया. 265 करोड़ रु. के कारोबार वाली इस सिगरेट कंपनी और इसके कुछ वितरकों पर करीब 200 करोड़ रु. की उत्पादकर चोरी का आरोप लगाया गया है. पिछले पखवाड़े उत्पादकर अधिकारी जीटीसी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे थे.

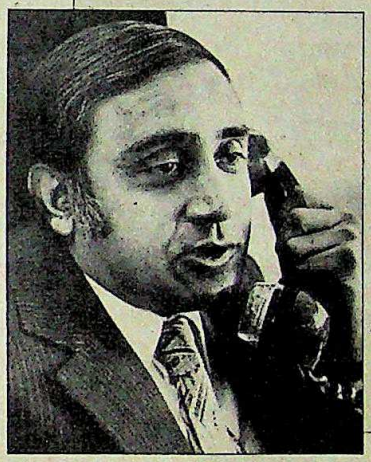

उत्पादकर की चोरी के मामले में जीटीसी के अध्यक्ष संजय डालमिया से छह घंटे पूछताछ की गई. उनका जवाब था कि कंपनी के रोज के कामों की जानकारी उन्हें नहीं होती

यह कदम पहले उठाए गए कुछ कड़े कदमों से अधिक ही कठोर होगा. कुछ महीने पहले उत्पादकर अधिकारियों ने इसी मामले में कंपनी के प्रमुख संजय डालमिया से दिल्ली में लगातार छह घंटे तक पूछताछ की थी. डालमिया ने अधिकारियों को यही जवाब दिया कि वे कंपनी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्हें कंपनी के रोज-रोज के कामों की जानकारी नहीं होती.

इस बीच, आयकर अधिकारियों ने कंपनी के जले पर और नमक छिड़क दिया. पिछली मई में उन्होंने कंपनी को नोटिस भेजकर 1984-85 के लिए 33 करोड़ रु. की अतिरिक्त आमदनी पर सवाल उठाया. कंपनी का कहना था कि यह राशि कई देसी कंपनियों के साथ हुए व्यापार में मिले कमीशन की है. लेकिन सरकार को संदेह है कि जीटीसी काला धन जमा कर रही है.

यही नहीं, दो महीने पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जीटीसी की एक याचिका रद्द कर दी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय उत्पादकर कानून राज्य में लागू नहीं होते. इस तरह जीटीसी को उत्पादकर का कुछ करोड़ बकाया भी चुकाना पड़ सकता है. मिजोरम के वाईरंगते में जीटीसी के लिए सिगरेट बनाने वाली नॉर्थ ईस्टर्न टुबैको (एनईटी) पर भी सरकार की 'कृपादृष्टि' बनी हुई है. इस साल अप्रैल के अंत में शिलंग में उत्पादकर अधिकारियों ने एनईटी को उत्पादकर की 16 लाख रु. की चोरी का नोटिस दिया.

जाहिर है देश की यह दूसरी सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी सरकारी तोप का निशाना बन चुकी है. इसी प्रक्रिया में एनईटी का मामला भी आ गया. साल भर पहले उत्पादकर अधिकारियों ने एनईटी से माल ले जा रहे ट्रक को इस आधार पर रोक लिया था कि इसमें पनामा वर्जीनिया सिगरेट को उत्पादकर चुकाने के फर्जी लेबल लगाकर ले जाया जा रहा है. इस पर जीटीसी ने एक प्रमाणपत्र पेश किया जो मिजोरम के तत्कालीन उत्पादकर आयुक्त ने दिया था. इस प्रमाणपत्र के अनुसार केंद्रीय उत्पादकर कानून मिजोरम में लागू नहीं होता. लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि उत्पादकर कानून मिजोरम में भी लागू होते हैं. यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में है.

लेकिन जीटीसी लगातार कहती आई है कि एनईटी से उसका तकनीकी गठबंधन भी है. फोन पर संपर्क करने पर संजय डालमिया ने इस मुद्दे पर बातचीत करने से इनकार किया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "एनईटी से हमारा तकनीकी सहयोग भर है, इससे अधिक नहीं. वह हमें सिगरेट देती है और हम उसे सिगरेट बनाने की तकनीक और विशेषज्ञ. वह एक स्वतंत्र कंपनी है."

पर चार महीने की छानबीन के बाद उत्पादकर विभाग के लोग कहते हैं कि यह बात पूरी तरह सही नहीं है. एनईटी एक ऐसा 'मुखौटा' है जिसके माध्यम से डालमिया की कंपनी व्यवसाय करती है. उत्पादकर अधिकारी दावा करते हैं कि उनके पास

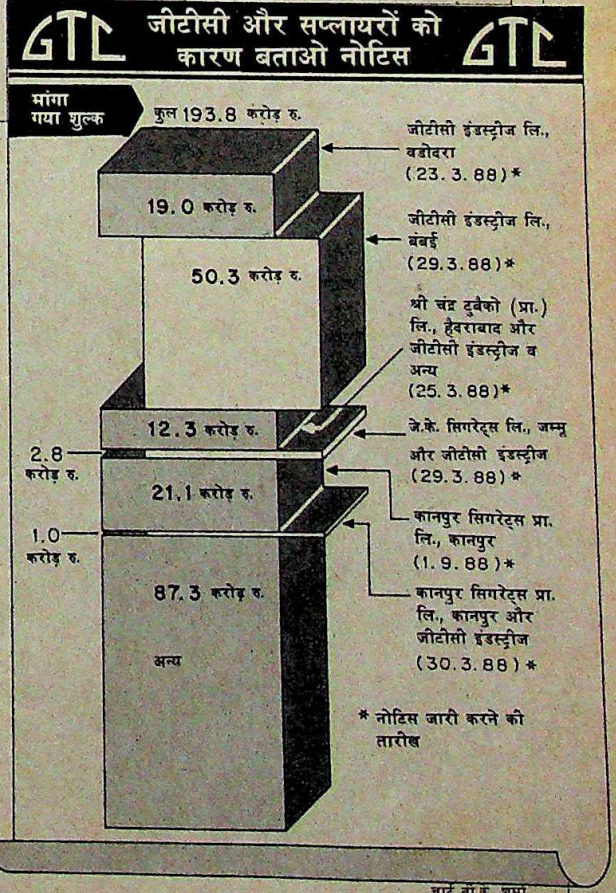

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिछाने व रखरखाव में बेहद आसान ● प्राकृतिक द्रव्यों से निर्मित ● स्वच्छ व स्वास्थ्यकर ● टिकाऊ व ध्वनिरोधक ● एक पोंछे में ही जगमगा उठे ● आकर्षक डिजाइनों, रंगों व मोटाई का एक अद्‌भुत संगम ● रूपयों की सही कीमत।

लिनोलियम

बहु उपयोगी फर्श बिछावन

इण्डिया लिनोलियम्स लिमिटेड, ९/१, आर. एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-७०० ००१

CCIL-1/88 HIN

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस बात के पक्के सबूत भी हैं.

सरकारी पक्ष का कहना है कि वाईरंगते में फैक्टरी लगाने की योजना जीटीसी ने मई 1987 में बनाई. स्थानीय कानूनों के अनुसार मिजो लोग ही मिजोरम में उद्योग लगा सकते हैं. कर अधिकारियों का कहना है कि इसी कारण जीटीसी ने दो स्थानीय लोगों के नाम से यह फैक्टरी लगवाई. ये दोनों असली मालिक नहीं हैं, एनईटी पर जीटीसी का ही पूरा नियंत्रण है. समझौते के अनुसार एनईटी को जीटीसी के ब्रांडों के अलावा किसी और तरह का सिगरेट बनाने की अनुमति नहीं है. जीटीसी की लिखित अनुमति के बिना वह अपने यहां तैयार माल बेच भी नहीं सकती.

सरकारी दावे के मुताबिक जीटीसी ने यह व्यवस्था भी कर ली कि एनईटी का अधिकांश माल जीटीसी की सहायक गोल्डेन इंवेस्टमेंट (सिक्किम) प्रा. लि. (जीआईएसएल) ही के माध्यम से बिका. इतना ही नहीं, तकनीक में सहयोग देने की जगह जीटीसी ने ही एनईटी लगाने के लिए पूंजी की व्यवस्था भी की. जीआईएसएल ने इसके लिए 10 लाख रु. का कर्ज मंजूर किया था. सरकारी दस्तावेजों के ही अनुसार 15 अप्रैल 1988 को दिए बयान में जीआईएसएल के निदेशक पी.के. चटर्जी ने स्वीकार किया कि जीटीसी ने ही एनईटी कंपनी बनाई थी. उन्हें पता था कि सिगरेट पर उत्पादकर नहीं दिया जाता है. इसके लिए उन्होंने जीटीसी के उपकार्यकारी निदेशक जे.पी. खेतान को लिखी अपनी चिट्ठी का हवाला दिया. अपनी चिट्ठी में चटर्जी ने सिक्किम में सिगरेट के भंडार वाली जगह को अच्छा परंतु उत्पादकर के दफ्तर पास होने से जोखिम वाला बताया है.

आयकर अधिकारियों ने कंपनी पर जो आरोप लगाए हैं, वे भी कम गंभीर नहीं. उनका कहना है कि जीटीसी ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और फ्लैक्ट इंडिया जैसी कंपनियों को टेलिफोन एक्सचेंज तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए कमीशन लेना माना है. (उन्होंने यह भी माना कि उसकी मदद से ही फ्लैक्ट ने प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स और नेशनल एल्युमिनियम कार्पोरेशन के आर्डर लिए गए). लेकिन आयकर अधिकारियों का कहना है कि प्रीमियर ने सीधे फ्लैक्ट को ही आर्डर दिए थे और अधिकांश कंपनियों ने ऐसा ही किया था.

यहां कई सवाल उठ खड़े होते हैं. क्या कोई कंपनी पैसों के मामले में इस तरह की गड़बड़ कर सकती है? निश्चित रूप से उसे यह पता होगा कि बाद में कर अधिकारी इस बारे में पूछताछ करेंगे? ये आरोप भी बहुत गंभीर हैं. लेकिन इस मामले में भी पक्का फैसला अदालत ही करेगी.

इस बीच, जीटीसी के खिलाफ चल रही जांच में कुछ रहस्यमय मोड़ भी आए हैं. चार वर्ष पहले 70 करोड़ रु. के उत्पादकर चोरी के चार मामले एकाएक स्थानीय उत्पादकर समाहरणालयों से दिल्ली स्थित निरीक्षण एवं लेखामहानिदेशक (उत्पादकर और सीमा शुल्क) के दफ्तर में मंगा लिए गए. तब से इन फाइलों पर धूल जम रही है.

इससे भी अजीब मामला उत्पादकर और सीमा शुल्क विभाग के अतिरिक्त समाहर्ता रमेश भट्टाचार्य का है. वे एनईटी के मामले में प्रमुख जांच अधिकारी थे. 27 मई को गुवाहाटी के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जी.के. चंगमाई की अदालत में दायर एक मामले में छात्रा मधुबाला वैश्य ने शिकायत की कि भट्टाचार्य ने उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार की कोशिश की. (इसी समय उत्पादकर विभाग ने जीटीसी के खिलाफ भट्टाचार्य के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत न करने पर मानहानि का मुकदमा दायर किया). लेकिन अदालत ने मधुबाला की शिकायत खारिज कर दी.

जीटीसी का कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन उत्पादकर अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी के वकील ने इसका फायदा उठाते हुए मानहानि वाले मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थगन आदेश की अर्जी दे दी. अदालत ने यह अर्जी भी खारिज कर दी. तब कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील की.

डालमिया से की गई पूछताछ के बारे में भी दो तरह की बातें कही जाती हैं. डालमिया कहते हैं, "शिलंग वाले मामले में मुझे पूछताछ के लिए कभी नहीं बुलाया गया. उत्पादकर अधिकारियों ने मुझसे सिर्फ दफ्तर में पेचीदा मसलों को विस्तार से बताने को कहा. हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि हमें परेशान न किया जाए."

लेकिन उत्पादकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि 18 अप्रैल को डालमिया को नोटिस भेजा गया था जिसमें उनसे अगले दिन उत्पादकर निदेशालय में हाजिर होने को कहा गया था. लेकिन वहां आने के बजाय 19 अप्रैल को डालमिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी. अदालत ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें 21 अप्रैल को निदेशालय में उपस्थित होने का आदेश दिया. लेकिन 20 अप्रैल को डालमिया दिल्ली के एक नर्सिंग होम में भर्ती हो गए और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया कि वे अस्वस्थ हैं. निदेशालय ने अदालत के आदेश की अवमानना का मामला दायर किया तो अदालत ने डालमिया को 11 मई को निदेशालय में जरूर हाजिर होने का आदेश दिया जिसे उन्होंने माना.

लेकिन इस पूरे प्रकरण में कितना दम है, यह अभी निश्चित करना मुश्किल है. सरकार जीटीसी को परेशान कर रही है या वह अनेक गलतियां करने वाली कंपनी को पकड़ रही है? अब इतना तय है कि अगर मामला लंबा खिचा तो इस सिगरेट कंपनी को यह महंगा जरूर पड़ेगा.

—सुरजीत बासगुप्त

आयकर अधिकारी जीटीसी के इस दावे को मानने को तैयार नहीं हैं कि उसने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्लैक्ट इंडिया जैसी कंपनियों को सुविधाएं प्रदान कर उनसे कमीशन लिया

महेंद्र पारीक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

तेजड़ियों का दौर

कम चर्चित शेयर भी उफान पर

देश के शेयर बाजारों के लिए यह एकदम गहमागहमी का दौर है. तेजड़ियों की तेजी देखते ही बनती है.

पिछले पखवाड़े शेयर मूल्य नित नए रिकार्ड बना रहे थे. ऐसा सिर्फ नामी शेयरों के साथ ही नहीं था. कम चर्चित शेयरों (हिंदुस्तान लीवर, इंडियन रेयॉन, मोदी रबर, गरवारे पोलिएस्टर) में भी काफी वृद्धि हुई. बाजार के हिसाब से मुश्किल माने जाने वाले एशियन पेंट्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, विमको और जेनिथ के शेयर भी धड़ल्ले से उठे.

और शेयरों की यही बढ़ोतरी शेयर मूल्य सूचकांकों में भी दिखी जिनके चढ़ने का कोई अंत ही नजर नहीं आया. 15 दिनों के अंदर ही इकानॉमिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक 46.6 अंक चढ़ गया. 14 सितंबर को यह 284.9 पर था और 5 अक्तूबर को

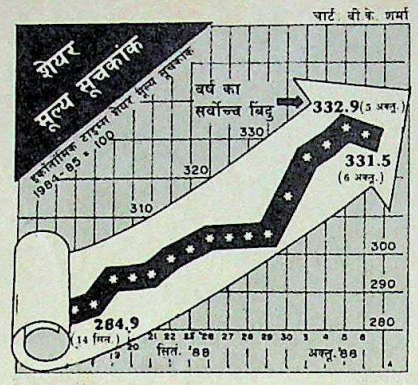

332.9 पर आकर रुका.

बाजार के इस उफान का एक और प्रतीक है बंबई शेयर बाजार के 30 शेयरों का सूचकांक, जो रिलायंस के शेयरों की हाजिर खरीद पर पांबदी लगने के बाद से सुस्त-सा पड़ा था, 2 अक्तूबर को यह सूचकांक अपने अब तक के सर्वोच्च बिंदु 676.58 तक जा पहुंचा. (इसके पहले का सर्वोच्च बिंदु 1986 में बजट-पूर्व की खरीद-फरोख्त में बना था) अगले दो दिनों में यह 686.97 पर चला गया.

कीमतों में इस कदर तेजी के कारण यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या इसके लिए सिर्फ सट्टेबाजी और अटकलबाजी ही जिम्मेवार है. शेयर बाजार के कुछ प्रमुख दलालों के अनुसार यह कारण कुछ हद तक ही जिम्मेवार है. बाजार की तेजी का असली कारण वित्तीय संस्थानों तथा साझा कोषों द्वारा लगातार की जा रही खरीद और कंपनियों के कामकाज की अच्छी खबरें ही हैं. मसलन, 6 अक्तूबर को ओरके सिल्क मिल्स ने बढ़ी हुई शेयर पूंजी पर भी प्रति शेयर लाभांश को 2 रु. से बढ़ाकर 2.10 रु. करने की घोषणा की. एस्कॉर्ट्स ने अपनी आठ महीनों की बिक्री में 32.5 फीसदी वृद्धि की घोषणा की.

अभी तक जिन उद्योगों में मंदी चल रही थी, वे भी बेहतर काम कर रहे हैं. हल्के व्यावसायिक वाहनों की बिक्री पिछले साल के 22,554 से बढ़कर 27,000 हो गई है. वैसे इस साल के पहले सात महीनों में कारों की बिक्री थोड़ी कम हो गई है लेकिन हिंद मोटर्स और प्रीमियर ऑटो ने अपनी गाड़ियों की अच्छी उठान की खबर दी है.

इन बातों को देखते हुए शेयर बाजार का उफान सही दिखता है. लेकिन हो सकता है कि यह थोड़ा नीचे आए. अगले पखवाड़े में ऐसा हो भी सकता है.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	बंद 5.10.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	60.00	30.25	57.50	6.50 +
एसोसिएटेड सीमेंट	278.00	128.50	263.00	0.50 +
एटलस कोप्को	65.00	33.50	62.00	10.50 +
एशियन पेंट्स	200.00	128.75	195.00	20.00 +
बजाज ऑटो	520.00	187.50	341.25	51.25 +
बड़ौदा रेयॉन	345.00	140.00	330.00	30.00 +
बाटा इंडिया	77.25	50.50	73.50	4.50 +
भारत फोर्ज	163.75	101.00	161.25	15.25 +
बिरला जूट	50.00	32.25	49.00	1.00 +
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	45.00	7.00 +
बॉम्बे डाइंग	159.50	94.00	133.00	14.00 +
ब्रिटानिया इंडिया	117.00	75.00	116.00	23.50 +
बुक बांड	120.50	75.00	118.50	16.50 +
सेंचुरी स्पिनिंग	1240.00	617.50	1230.00	190.00 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	76.00	8.00 +
कोलगेट	297.50	160.00	291.25	25.00 +
सायनामिड	65.00	33.00	60.00	—
डीसीएम	51.00	28.00	49.00	6.88 +
डनलप	86.50	66.00	81.00	10.00 +
ईआई होटल्स	60.00	38.00	52.50	0.50 +
एस्कार्ट्स	71.50	37.00	67.00	11.00 +
फिनोलेक्स केबल्स	435.00	237.50	332.50	45.00 +
फूड स्पेशिलिटीज	174.00	93.50	168.50	15.00 +
गरवारे नाइलोन	56.00	20.00	51.00	6.00 +
जी.ई. शिपिंग	38.50	20.80	35.75	3.50 +
गुजरात स्टेट फर्टि.	172.00	75.00	168.00	7.00 +
ग्रासिम इंडिया	118.00	81.50	114.00	6.00 +
हिंडु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	113.00	7.00 +
हिंदुस्तान सिबा	650.00	332.50	650.00	85.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	116.25	17.25 +
हिंदुस्तान लीवर	88.00	59.50	85.50	12.50 +
हिंदुस्तान मोटर्स	29.25	15.80	27.90	1.20 +
आई.ई.एस.	47.50	31.00	44.75	6.25 +
इंडियन आर्गेनिक	46.50	15.00	46.50	15.00 +
इंडियन रेयॉन	80.50	46.00	78.00	8.50 +
इंडाल	253.75	133.75	253.75	40.00 +
इंगरसॉल-रैंड	340.00	205.00	340.00	17.50 +
आई.टी.सी.	56.00	30.00	54.50	5.00 +
जे.के. सिंथेटिक्स	86.50	45.50	83.50	8.00 +
काइनेटिक इंजी.	290.00	161.25	267.50	10.00 +
किर्लोस्कर क्युमिस	88.75	48.00	83.75	13.75 +
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	295.00	10.00 +
लारसन-टुब्रो	140.50	75.50	140.00	16.50 +
लिप्टन	76.00	52.00	74.00	6.50 +
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	13.50	0.50 +
मदुरै कोट्स	85.00	59.00	83.50	4.50 +
महिंद्रा-महिंद्रा	103.00	48.50	103.00	25.00 +
मिल्क फूड	230.00	72.50	221.25	8.75 +
मोटर इंडस्ट्रीज	670.00	447.50	660.00	20.00 +
मुकुंद आयरन	114.00	72.50	110.00	16.00 +
नेशनल आर्गेनिक	810.00	390.00	810.00	145. +
निरलॉन	16.00	5.00	11.25	0.75 +
ओरके सिल्क मिल्स	51.00	17.00	40.50	7.75 +
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	37.00	24.50	37.00	8.25 +
फाईजर	79.50	50.00	70.00	9.00 +
प्रीमियर ऑटो	48.50	23.00	45.75	10.75 +
रैनबेक्सी	120.00	68.00	81.25	9.75 +
रेमंड	96.00	41.50	60.00	1.00 +
रॉलिंट ऐंड कोलमैन	227.00	120.00	152.00	18.00 +
रिलायंस इंडस्ट्रीज	231.00	69.00	191.00	4.00 —
शॉ वैलेस	132.00	50.50	69.50	12.00 +
श्रीराम फाइबर्स	62.50	32.50	53.00	1.50 +
सीमेंस इंडिया	92.50	56.00	90.00	5.00 +
एसकेएफ बैयरिंग्स	1950.00	1058.00	1940.00	300.00 +
स्प्रिंक	60.25	23.50	53.00	4.75 +
टाटा स्टील	946.25	568.75	940.00	28.75 +
टेल्को	782.50	340.00	772.50	35.00 +
वाम आर्गेनिक	115.00	75.00	114.00	21.00 +
वोल्टास	500.00	225.00	440.00	5.00 —
विम्को	24.00	11.00	23.50	4.00 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	11.7240	11.5770
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1267	1.1094
बहरीन	दीनार	1	39.0918	39.0000
बांग्लादेश	टका	100	47.2122	47.0926
कनाडा	डालर	1	12.2006	12.0534
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0584	2.0323
मिस्र	पौंड	1	6.9326	6.8928
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3585	2.2962
हांगकांग	डालर	1	1.8862	1.8636
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0860	0.08000
ईरान	रियाल	100	20.6223	20.5430
इटली	लीरा	100	1.0400	1.0000
जापान	येन	100	11.1982	10.9170
केन्या	शिलिंग	1	0.7962	0.7332
कुवैत	दीनार	1	51.0230	50.6922
मलेशिया	डालर	1	5.4914	5.4267
मारीशस	रुपया	1	1.0429	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6426	0.6002
हालैंड	गिल्डर	1	7.0199	6.9315
पाकिस्तान	रुपया	1	0.8122	0.7422
सिंगापुर	डालर	1	7.2302	7.1422
स्पेन	पेसो	1	0.1200	0.1171
श्रीलंका	रुपया	1	0.4500	0.4100
स्वीडन	क्रोना	1	2.3100	2.2795
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.3133	9.1989
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1368	0.1215
थाईलैंड	बहत	100	57.7622	57.6922
ब्रिटेन	पौंड	1	24.8756	24.7402
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	14.7384	14.5668
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.9860	3.9010
सोवियत संघ	रूबल	1	16.8969	16.2960
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.0321	7.8309

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 6.10.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या बेजान पत्रिकाओं की भीड़ में आप ढूँढ रहे हैं एक जानदार-जानकार पत्रिका ?

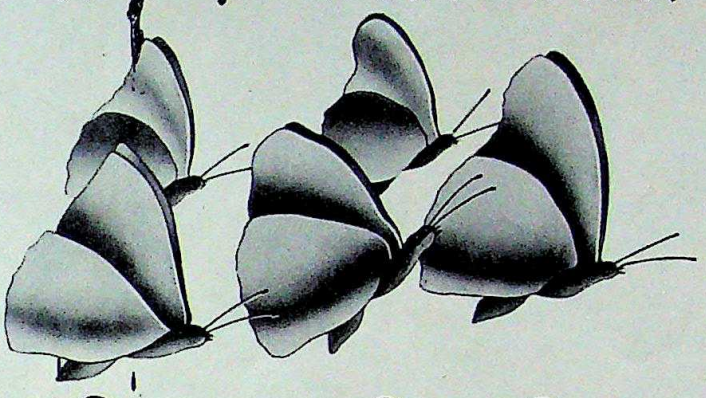

तो पढ़िए साप्ताहिक हिन्दुस्तान

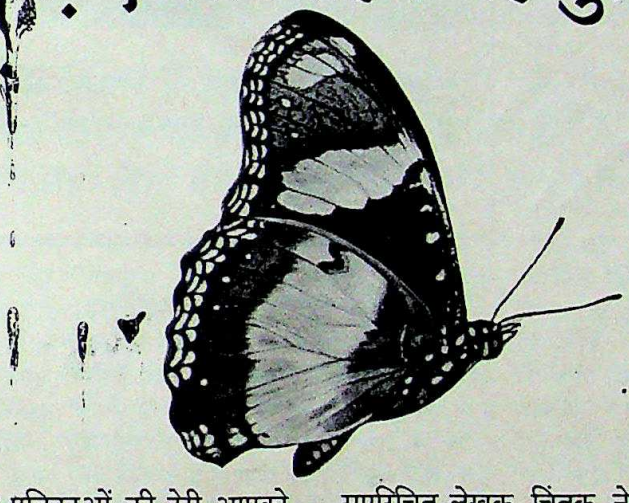

अगर बेजान और नीरस पत्रिकाओं की ढेरी आपको उबाने लगी है तो इनका साथ छोड़िए और उठाइए साप्ताहिक हिन्दुस्तान। आप जिसमें पाएंगे दुनिया भर की जानकारियां, नई प्रेरणा, नये अहसास, नये पत्र, नये तेवर और नये कलेवर। अनेकों नये-नये स्तम्भ, अछूते विचार, आकर्षक छपाई और साजसज्जा में।

इसमें अब विविध विषयों पर अधिक व्यापक, गहन और विस्तृत सामग्री दे रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध और सुपरिचित लेखक, चिंतक, नेता और पत्रकार निखिल चक्रवर्ती, डा० इरफान हबीब, डा० धर्मवीर भारती, शिवानी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

अब बदलाव का फैसला कर ही डालिए।

और पढ़िए—
साप्ताहिक हिन्दुस्तान

साप्ताहिक हिन्दुस्तान

बदलते वक्त की सही पहचान

React/1292A/88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बर्मा

बगावत का बढ़ता दायरा

छात्र हथियारबंद होने लगे

थाईलैंड की सीमा से लगी पूर्वी बर्मा की पहाड़ियों के ऊपर से सुबह की धुंध छंटते ही थाई बॉ बो जंगल शिविर में रहने वालों को सामूहिक जलपान के लिए लाउडस्पीकर से घोषणा की गई. सैकड़ों उत्साही नौजवान और कुछ महिलाएं भी बांस की मेजों के चारों ओर बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगे. उन्हें रोज चावल, दाल और मछली की चटनी परोसी जाती है.

शहरी कपड़े पहने ये नौजवान, जिनमें कुछ चश्मे भी पहने हुए हैं, कारेन और दूसरे वनवासियों से एकदम अलग दिखते हैं. घने जंगलों वाली थाई-बर्मा सीमा पर इन पहाड़ियों में सक्रिय वनवासियों के बीच ये नौजवान वही हैं जो 18 सितंबर को रंगून में सत्तापलट के बाद जनरल सा मांग की सैनिक सरकार के दमन से भागकर इधर आए हैं. उस दिन 400 से अधिक छात्र फौज की गोलियों का निशाना बने थे.

पिछले पखवाड़े करीब 5,000 से 10,000 छात्रों और दूसरे लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने दूरदराज के इसी पहाड़ी इलाके में शरण ली है. यह इलाका बर्मा के अनेक विद्रोही समूहों का कार्यक्षेत्र रहा है. इनमें कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी, कारेनी आर्मी, मोन नेशनल लिबरेशन आर्मी शामिल हैं. देश के सुदूर उत्तर में काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी सक्रिय रही है. ये बागी बर्मा संघ के अंतर्गत ही स्वायत्तता की लड़ाई लड़ रहे हैं.

रंगून कला एवं विज्ञान विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के स्नातकोत्तर छात्र, 29 वर्षीय ला आउंग कहते हैं, "शहरों में जन प्रदर्शनों का दौर अब खत्म हो गया है. सेना की गोलियां खाने का कोई मतलब नहीं. हमें लगता है कि सेना के अधिकारी अपनी मर्जी से गद्दी नहीं छोड़ेंगे. इसीलिए हम लोग सशस्त्र संग्राम की तैयारी कर रहे हैं." आउंग अब

एशिया वीक

हम सिर्फ जंगल में लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं बनना चाहते हैं. हमारा इरादा यह सीखने का है कि शहरी गुरिल्ला लड़ाई कैसे लड़ी जाती है

ऑल बर्मा स्टुडेंट्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के महासचिव हैं. फ्रंट थाई बॉ वो शिविर में प्रशिक्षण ले रहे सभी 1800 लोगों को अपना सदस्य बताता है. सीमावर्ती इलाकों से चलने वाले दूसरे छात्र शिविरों से भी उसके संपर्क हैं.

करीब 100 लड़कियां भी फ्रंट की सदस्य हैं. इनमें से एक हैं रंगून विश्वविद्यालय की ही 19 वर्षीया मी मी. वे कहती हैं, "हमें लड़ना ही होगा. एक तरफ तो सैनिक शासक रंगून में छात्रों को गोलियों से उड़ा रहे हैं और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ वे आम चुनाव कराने और लोकतंत्र बहाल करने के वादे कर रहे हैं. हमें हथियारबंद होकर लड़ाई लड़नी है. मैं मरने से नहीं डरती."

थाइ बॉ बो में रहने वाले किसी भी छात्र को नहीं लगता कि सशस्त्र संग्राम के उनके फैसले और प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा रंगून में खुली लड़ाई लड़ने में किसी तरह का विरोधाभास है. वे मानते हैं कि उनका संघर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ऊ नू, पूर्व ब्रिगेडियर जनरल औंग ग्यी, पूर्व जनरल तिन ऊ और औंग सन सू ची की अगुआई वाले आंदोलन का पूरक ही है. सू ची बर्मी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता औंग सन की बेटी हैं. इन चारों नेताओं की अगुआई में 24 सितंबर को नेशनल यूनाइटेड फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी की घोषणा की गई थी. एक छात्र ने कहा, "यह सारा कुछ लोकतांत्रिक आंदोलन का ही हिस्सा है. हां, रास्ते जरूर अलग-अलग हैं. वनवासी विद्रोही भी हमारे भाई हैं."

नौजवान छात्र वनवासी विद्रोहियों के साथ हाथ मिलाने के मामले में भले ही एकमत हैं पर सा मांग की सैनिक सरकार के खिलाफ सशस्त्र संग्राम छेड़ने का उनका तरीका निश्चित रूप से एकदम अलग होगा. ला आउंग कहते हैं, "हम महज जंगल में पनाह लेने वाले बागियों की एक और सेना नहीं बनाने जा रहे. हमारी मंशा शहरी छापामार युद्ध शैली सीखना है ताकि हम सैनिकों के खास ठिकानों, पेट्रोल पंपों और उन घृणित सैनिक अधिकारियों पर हमला कर सकें जिन्होंने अगस्त और सितंबर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे."

थाई बॉ बो में रहने वाले छात्रों का कहना है कि भले ही वे शहर छोड़कर जंगल में आ गए हैं पर वहां लोगों से अभी भी उनके भूमिगत संबंध बरकरार हैं. वे अपने पास स्टेनगनें, 303 इनफील्ड राइफलें और पिछले महीने सत्तापलट के बाद रंगून के थानों से लूटे गए कुछ स्वचालित हथियार होने का दावा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बटिल लिटनर

थाई बॉ बो शिविर के छात्रों का कहना है कि वे भले ही शहरी इलाके छोड़कर जंगलों में चले गए हैं, लेकिन शहर में उनका भूमिगत संगठन अभी भी काम कर रहा है और उनके मरजीवड़े दस्ते सेना को नाकों चने चबवा सकते हैं

करते हैं. इसके साथ ही वे रंगून के लों से लूटे गए कुछ स्वचालित हथियार ने का दावा भी करते हैं. इसके साथ ही होंने रंगून में चोरी-छिपे बेचे जाने वाले ने निर्मित एम-36 हथगोले खरीदकर खानी में और 'सुरक्षित जगहों' पर रख ा है. ये गोले 35 क्यात (करीब 70 ए) में खरीदे जा सकते हैं. यह दावा सही तो इसका मतलब है बर्मा में भी मरजीवड़े ने बन गए हैं जिन्हें नियंत्रित करने में सेना ी नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं.

लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भले ी छात्रों में हिम्मत और निष्ठा का अभाव हीं और न ही शहरी गुरिल्ला युद्ध के लिए हें जनसमर्थन की कमी है, फिर भी उनका ामना युद्धों में तपी बर्मी सेना से है. एक विश्लेषज्ञ ने कहा, "बर्मा की अनुशासित सेना 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से ही छोटे बागी समूहों से निबटती आई है. उसने यह भी दिखा दिया है कि शहरों में आंतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर भी वह बिना किसी झिझक के गोली चला सकती है. विपक्ष को लोगों के भारी समर्थन के बावजूद जीत आसानी से मिलने वाली नहीं है."

दूसरे सूत्रों का कहना है कि इन छात्रों को शरण देने वाले बागी गुटों को भी अब हथियार और गोला-बारूद की कमी होने लगी है. यहां तक कि प्रशिक्षण देने की उनकी सुविधाएं भी सीमित बताई जाती हैं. किसी बाहरी देश ने अब तक इन छात्रों को मानवीय आधार पर कुछ सहायता देने के अलावा सैनिक सहायता देने की पहल नहीं दिखाई है. बैंकाक के एक राजनैतिक प्रशिक्षक का कहना है, "बर्मा को सहायता देने वाले मुख्य देशों—अमेरिका, जापान और पश्चिमी जर्मनी ने वर्तमान सरकार से अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए बर्मा को दी जाने वाली सहायता रोक दी है. लेकिन सरकार का विरोध करने वालों को हथियार और गोला-बारूद देना एकदम अलग चीज है."

दो इस्लामी बागी समूहों ने 500 से अधिक मुसलमान छात्रों का हवाला देते हुए इस्लामी देशों से हथियार और गोला-बारूद देने की मांग की है. लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है. ये दो संगठन हैं—मुस्तफा कमाल उर्फ क्याब ला के नेतृत्व वाली मुस्लिम लिबरेशन आर्गेनाइजेशन ऑफ बर्मा और डॉ. अब्दुल रजाक की अध्यक्षता वाला कावथूलेई मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट.

दक्षिण-पूर्व एशियाई मामलों के अधिकांश जानकारों का मानना है कि खुद सेना के अंदर से ही बुनियादी बदलाव की धारा निकलेगी. फिलहाल सेना ही देश की सबसे शक्तिशाली जमात है. लेकिन अभी तक तो इसमें अंदरूनी दरार आने के कोई संकेत नजर नहीं आते. पर पिछले पखवाड़े की घटनाओं के बाद इस स्थिति में बदलाव आ सकता है. थाई बॉ बो में रह रहे एक छात्र ने कहा, "पहले सेना को वनवासी और अल्पसंख्यक समूहों से ही लड़ना होता था. लेकिन हम लोग बर्मी हैं और हममें से अनेक के रिश्तेदार सेना में हैं. जब किसी अधिकारी को अपने बेटे, भतीजे, या दूसरे रिश्तेदारों पर ही गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा, तब स्थिति निश्चित रूप से कुछ और मोड़ लेगी. इसलिए हमें नहीं लगता कि सैनिक जनरलों के प्रति अभी जो वफादारी दिखती है, वह सदा रह पाएगी."

लेकिन ऐसी स्थिति अभी निकट भविष्य में बनती नजर नहीं आती. इसलिए छात्रों का पाला एक असंभव-सी दिखने वाली मुश्किल से पड़ा है. थाई बॉ बो में रहने वाले अधिकांश छात्र मलेरिया, दस्त या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं. ये बीमारियां उन्हें मध्य बर्मा के दुश्वार पहाड़ी इलाकों को पार करके इन विद्रोहियों तक पहुंचने के दौरान लगीं. रंगून के शासकों के खिलाफ बर्मी लोगों का संघर्ष अभी शैशवावस्था में ही लगता है.

—**बटिल लिटनर,** पूर्वी बर्मा के थाई बॉ बो में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडियन एअरलाइंस

लापरवाही व लेट-लतीफी की लपेट में

ठिकाने पर तुरत-फुरत, आरामतलबी से पहुंचना हो तो हवाई यात्रा करो—यह कहने के दिन अब लदते जा रहे हैं. इंडियन एअरलाइंस की उड़ानें अब स्वास्थ्य के लिए जोखिम बन चुकी हैं. उसकी घटिया सेवाओं, लेट-लतीफी और 'चलता है' के नजरिये से यात्रियों के चेहरे लाल-पीले होते रहते हैं. एक रिपोर्ट:

इंडियन एअरलाइंस की किसी उड़ान में सीट हासिल करना इन दिनों बड़ी उपलब्धियों में शुमार हो गया है. इसके लिए आकाश-पाताल एक कर देना पड़ता है. एअरलाइंस महकमे या नागरिक उड्डयन विभाग में ऊंची पैरवी भिड़ानी पड़ती है. और इतना कुछ करने के बाद पक्का टिकट मिल जाए तो यह मत मानिए कि परेशानी खत्म हो गई. इधर कुछ हफ्तों से इस विमान सेवा के यात्रियों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.

पिछले कुछ महीनों से इसकी तकरीबन आधी उड़ानें या तो रद्द होती रही हैं या देर से चलती हैं. और इन सबके नतीजे काफी भयंकर होते हैं. अमृता कुमार का ही उदाहरण लिया जाए. 8 अगस्त को एअरलाइंस ने लेह से नई दिल्ली की अपनी उड़ान रद्द कर दी. और अमृता लेह की ठिठुरती वादियों में ही फंस गईं. लेह में एअरलाइंस कार्यालय के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह टिकटों का पैसा वापस कर पाता या यात्रियों को श्रीनगर भेजने के लिए बस का इंतजाम कर पाता. फंसे हुए यात्रियों के लिए होटलों में रहने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया. अमृता व 10 दूसरे यात्रियों को एक खुले ट्रक के पीछे बैठकर श्रीनगर तक 40 घंटे की यात्रा करनी पड़ी. और वहां पहुंचकर पता चला कि नई दिल्ली की उड़ानों में 2 सितंबर तक कोई जगह नहीं मिल सकती है.

यात्री कभी भी नहीं समझ सकता कि एअरलाइंस कब क्या कर बैठे. बंबई में कुछ यात्री बंगलूर जाने वाली एअरबस पर सवार हुए ही थे कि घोषणा हुई कि विमान में कुछ खराबी है. वे नीचे उतर गए. पर तुरंत ही यह विमान दिल्ली जाने वाले यात्रियों से भर गया जिनमें कुछ 'वीआईपी' भी थे. विमान राजधानी की ओर उड़ गया.

यात्रियों का कहना है कि लापरवाही और उदासीनता इंडियन एअरलाइंस के पुराने रोग हैं. इसके अध्यक्ष राहुल बजाज तक कहते हैं, "बिना प्रतिस्पर्धा के हम सुधर नहीं सकते. इंडियन एअरलाइंस के पास इनाम या सजा देने का कोई अधिकार नहीं. हम घोड़े और गधे को एक ही डंडे से हांकते हैं." ज्यादातर मामलों में यात्रियों को तकलीफ इसलिए झेलनी पड़ती है क्योंकि एअरलाइंस तरीके से काम नहीं करती. मिसाल के लिए दिल्ली जाने वाले, 200 मुसाफिरों से भरे इसके एक विमान को अचानक लखनऊ की तरफ मोड़ दिया गया. लखनऊ दिल्ली की वैकल्पिक हवाई पट्टी है. पर यह एअरबस जब लखनऊ के हवाई अड्डे पर उतरी तो मुसाफिरों को एअरबस पर ही बैठे रहना पड़ा क्योंकि वहां उन्हें उतारने के लिए सीढ़ी ही नहीं थी.

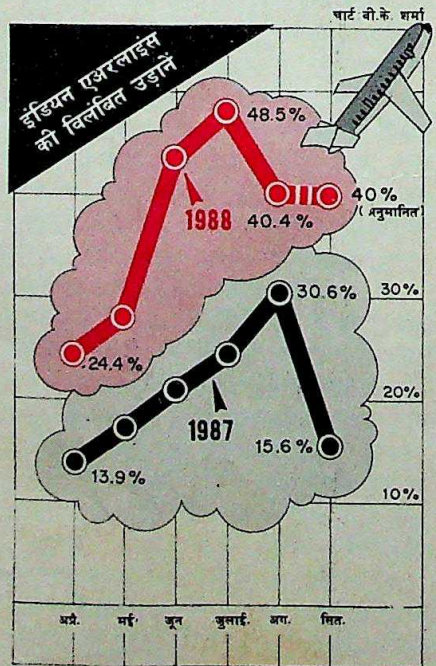

सार्वजनिक निकायों पर बनी एक समिति की बैठक में इस घटना का जिक्र खास तौर पर किया गया. एअरलाइंस के प्रतिनिधि ने आरोप राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर लगाया क्योंकि वही लखनऊ हवाई अड्डे का प्रबंध संभालता है. पर प्राधिकरण का कहना है कि हवाई अड्डे के सारे उपकरणों का इंतजाम खुद एअरलाइंस ही करती है. अब रांची के जीर्ण-शीर्ण, छोटे-से हवाई अड्डे को कलकत्ता की वैकल्पिक हवाई पट्टी बनाया गया है. वहां भी एअरबस के लिए सीढ़ियां तो नहीं ही हैं, बुनियादी सुविधाएं भी नदारद हैं. अगर कलकत्ता जा रही किसी एअरबस को रांची की ओर मोड़ देना पड़े तो इससे पैदा होने वाली दिक्कतों का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है.

लेकिन यात्रियों को सबसे ज्यादा तकलीफ लापरवाही से विमान उड़ाने वाले पायलटों से होती है. इसके चलते खुद उनकी और यात्रियों की जान हरदम जोखिम में रहती है. वे कुछ भी कर सकते हैं. एअरलाइंस का एक बोइंग-737 कलकत्ता हवाई अड्डे पर 8 फरवरी, 1985 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसके दो पायलट कैप्टन नांगिया और चंदोक विमान के पहिये निकालना 'भूल' गए थे. विमान बरबाद हो गया और उसके 100 यात्री मौत के मुंह से बाल-बाल बचे. 18 जून 1988 को दिल्ली के हवाई अड्डे पर ऐसी ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

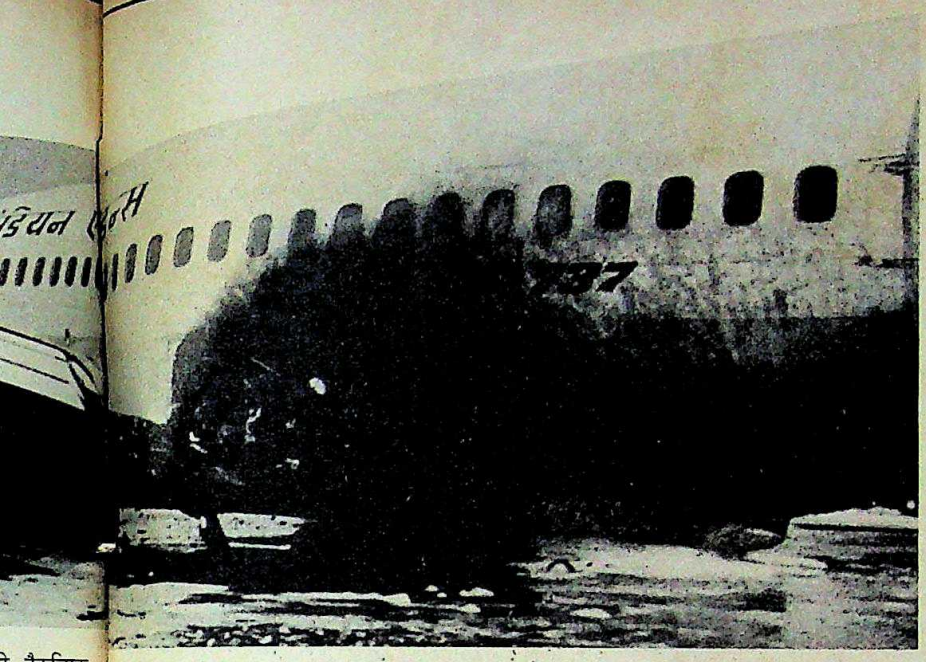

हवाई पट्टी पर पड़ा दुर्घटनाग्रस्त विमानः यात्रा का जोखिम

उड़ान के पहले डॉक्टर पायलटों की जांच करते हैं कि वे शराब तो नहीं पिए हुए हैं. इस जांच रिपोर्ट की कई पुर्जियों पर एक साथ ही दस्तखत करके रख दिया जाता है और पायलट को उस पर सिर्फ अपना नाम, तारीख और उड़ान संख्या भरनी होती है. पायलटों के रक्तचाप और नाड़ी दर को तो दर्ज भी नहीं किया जाता. पायलट मौसम और एटीसी संबंधी हिदायतों पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं. मसलन खराब मौसम के दौरान तिरुचिरापल्ली में 737 विमान को उतारने की कोशिश में विमान का एक डैना मुड़-तुड़ गया लेकिन पायलट ने विमान को पास ही मदुरै में उतारने के बजाय बुरी तरह क्षति-ग्रस्त डैने के साथ वापस मद्रास की तरफ मोड़ लिया. डीजीसीए ने पायलट का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की.

विमान से पक्षियों का टकराना तो लगभग रोज की घटना होती जा रही है. पक्षियों के टकराने से विमान को अक्सर कोई खतरा तो नहीं होता पर इससे यात्रियों का मन एकदम खट्टा हो जाता है. भारत के शहरों में मंडराने वाले चीलों, बाजों आदि का वजन 25 किलो तक हो सकता है. यदि एक भी पक्षी जेट इंजन के भीतर घुस आता है तो इससे इंजन तो लगभग खराब हो ही जाता है. विमान के केबिन में भी मांस और पंखों के जलने की दुर्गंध फैल जाती है.

क्या मौजूदा संकट इंडियन एअरलाइंस की किसी गंभीर बीमारी का परिचायक है? इसका उत्तर शायद हां ही हो. कलकत्ता की विमान दुर्घटना की जांच से पता चला कि उसके पायलटों नांगिया और चंदोक के बीच 'बातचीत तक बंद' थी. इसलिए पायलट ने स्टैंडर्ड चेक-लिस्ट नहीं मांगी और सहायक पायलट मुंह फुलाए बैठे रहे. वैसे, इंडियन एअरलाइंस के दफ्तर में भी मुंह फुलाने की प्रवृत्ति इन दिनों जोरों पर है. एअरलाइंस के निदेशक मंडल के एक सदस्य ने कहा, "प्रबंध निदेशक और उनके तीन उप-प्रबंध निदेशकों के बीच बातचीत लगभग बंद ही है."

एअरलाइंस के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत संबंधों में तनाव और संवाद की कमी के दूरगामी नतीजे हो रहे हैं. विभागों के बीच संपर्क क्षीण हो गया है, प्रबंधकों और मजदूर संघों के बीच संबंध तनावपूर्ण होते गए हैं. कर्मचारियों और भारी वेतनभोगी पायलटों का मनोबल भी लगभग डगमगा चला है. हाल ही में जब एक अरब एअरलाइंस का पायलटों का विज्ञापन आया तो इंडियन एअरलाइंस के करीब 200 पायलटों ने वहां नौकरी के लिए आवेदन किया.

सबसे परेशानी की बात तो यह है कि फिलहाल एक असहायता का माहौल ही बरकरार है. हालात सुधर नहीं पा रहे हैं. और नेतृत्व में खामी तो है ही. प्रबंधकों ने नए वेतनमान पर समझौते के लिए अभी तक मजदूर संघों से बातचीत भी शुरू नहीं की है. पुराना समझौता 1985 में ही खत्म हो गया. इसी तरह 1986-87 के बोनस का मामला भी तय नहीं हुआ है और अब 1987-88 का बोनस देने का समय भी आ पहुंचा है.

बजाज स्वीकार करते हैं, "देरी वाली समस्या तो महज आधी समस्या है. बाकी

चार्ट: बी.के. शर्मा

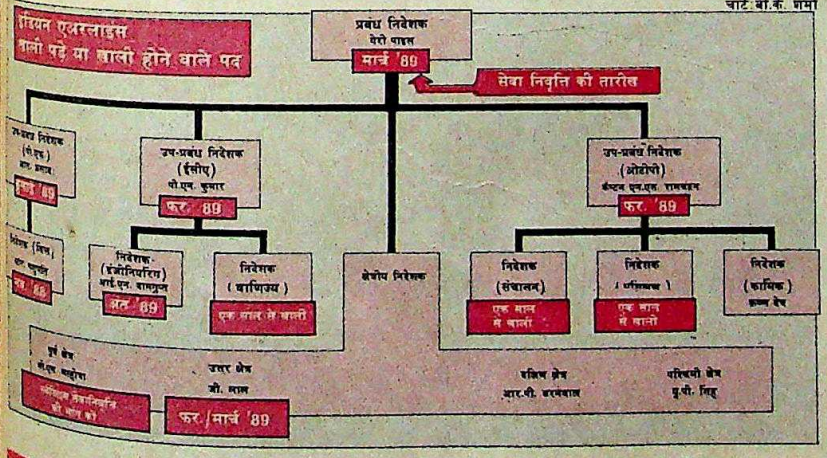

उत्तराधिकारी तय करने की प्रणाली न होने से फैसले करने की प्रक्रिया ही पंगु हो गई है. इसका असर तो तब दिखेगा जब प्रबंध निदेशक और दो उप-प्रबंध निदेशक रिटायर होंगे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समस्या तो देरी के बाद पेश होती है. यहां सवाल उठता है कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का." हालात बदल पाने में असहायता महसूस करते हुए बजाज ने पद त्याग तक की सोची.

लेकिन आला प्रबंधकों के पदों पर उत्तराधिकारी तय करने की प्रणाली के अभाव ने फैसले करने की प्रक्रिया को पंगु कर दिया है. इसका असर तब महसूस किया जाएगा जब प्रबंध निदेशक गैरी पाइस और तीन में से दो उप-प्रबंध निदेशक पी.एन. कुमार और कैप्टन एन.एस. रामचंद्रन मार्च 1989 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे. इसके चार महीने बाद उप-प्रबंध निदेशक आर. प्रसाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. आम तौर से इन आला पदों को निदेशक स्तर के 10 विभागीय प्रधानों को पदोन्नति देकर भरा जाता है. पिछले एक साल से तीन-तीन निदेशकों—वाणिज्य निदेशक, संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक— के पद खाली पड़े हैं. इस साल के अंत तक वित्त निदेशक भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) मार्च 1989 तक. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) ने अपनी मर्जी से समयपूर्व अवकाश ग्रहण कर लिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अगले मार्च तक चार आला पदों के लिए निदेशक स्तर के 10 में से केवल चार अधिकारी उपलब्ध रह जाएंगे (देखें चार्ट).

विमानों से पक्षियों के टकराने की हाल की घटनाओं के बाद एअरलाइंस और हवाई अड्डा अधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है. पिछले पखवाड़े नागरिक उड्डयनमंत्री के साथ हुई बैठक में एअरलाइंस अधिकारियों ने ज्यादातर उड़ानों में देरी की वजह पक्षियों से टकराव की घटनाएं बताई. लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष एन.के. सिंह कहते हैं कि हकीकत यह नहीं है. "60 फीसदी घरेलू उड़ानों की व्यवस्था करने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाएं 1985 के प्रति 10,000 उड़ानों में 6.56 से घटकर 1987 और 1988 में तकरीबन 3.91 हो गईं.

पिछले साल पक्षियों से टकराव की दो-तिहाई घटनाएं राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे हवाई अड्डों के

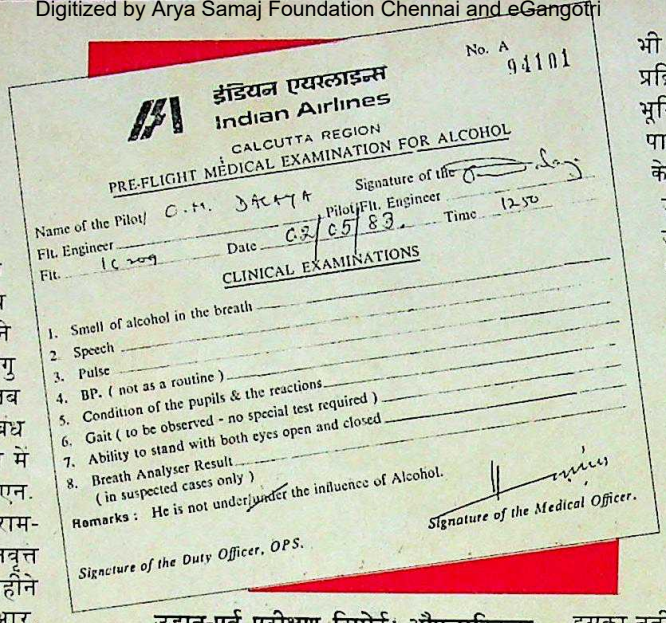

No. A 94101

इंडियन एयरलाइन्स
Indian Airlines
CALCUTTA REGION
PRE-FLIGHT MEDICAL EXAMINATION FOR ALCOHOL

Name of the Pilot/ O.M. DACAYA Signature of the Pilot/Flt. Engineer
Flt. Engineer
Flt. IC 209 Date 02/05/83. Time 1250

CLINICAL EXAMINATIONS

1. Smell of alcohol in the breath
2. Speech
3. Pulse
4. BP. (not as a routine)
5. Condition of the pupils & the reactions
6. Gait (to be observed - no special test required)
7. Ability to stand with both eyes open and closed
8. Breath Analyser Result (in suspected cases only)

Remarks : He is not under/~~under~~ the influence of Alcohol.

Signature of the Medical Officer.

Signature of the Duty Officer, OPS.

उड़ान-पूर्व परीक्षण रिपोर्ट: औपचारिकता

नजदीक हुई. इसके अध्यक्ष अनुभवी पायलट और नागरिक उड्डयन के पूर्व महानिदेशक एअर मार्शल सी.के.एस. राजे का सवाल है कि क्या इंडियन एअरलाइंस के पायलट पक्षियों से बचने के उपायों पर अमल भी करते हैं. राजे का कहना है, "इस प्रक्रिया में विमान चालक दल की भी भूमिका होती है. ज्यादातर भारतीय पायलट विमान को दूर तक दौड़ाने के बाद उड़ान भरना पसंद करते हैं. उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो उड़ान भरने से पहले हवाई पट्टी पर अथवा आकाश में पक्षियों की मौजूदगी की जांच भी करते हैं." पाइस नाराजगी भरे स्वर में आरोपों का खंडन करते हैं. उनका कहना है कि देरी की असल वजह है क्षमता की कमी. साफ-साफ कहें तो इंडियन एअरलाइंस के पास विमानों की बेहद कमी है. यह कमी कुछ तो अपनी बनाई हुई है और कुछ दुर्घटनाओं की वजह से. इसका नतीजा यह है कि उड़ान में किसी भी कारण देरी होने पर अतिरिक्त विमान उपलब्ध नहीं होते. एक उड़ान में देरी का अर्थ है कम-से-कम चार लगातार उड़ानों में देरी, क्योंकि एक बोइंग-737 दिन में पांच से छह उड़ान भरता है.

नामस भोजानी

अगले हफ्ते पट्टे पर लिए गए चार 737 विमान आ रहे हैं जो एअरलाइंस की विमान क्षमता में इजाफा करेंगे. और साल में 3,000 घंटों से ज्यादा उड़ाए जाने वाले मौजूदा बोइंग का बोझ हल्का करेंगे. लेकिन इंजीनियरिंग विभाग मुसीबत में फंस गया है क्योंकि साल में तकरीबन 2,600 घंटे इस्तेमाल के बाद वे विमानों की देखभाल करते हैं. उड़ान के अतिरिक्त घंटों की वजह से रखरखाव के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाता. पायलट द्वारा विमान की प्रणाली में खराबी की शिकायत मजबूरन टाल देनी पड़ती है. इसकी वजह से पायलट खफा हो जाते हैं और पायलटों व इंजीनियरों के संबंधों में तनाव पैदा हो जाता हैं.

इंडियन एअरलाइंस के आशावादियों को उम्मीद की किरण नजर आती है. वे कहते हैं कि अगले साल इस वक्त क्षमता की बात अतीत की बात हो जाएगी क्योंकि 19 नई 320 एअरबसें आनी शुरू हो जाएंगी. 160 सीटों वाले 19 विमानों के शामिल हो जाने से तो प्रतीक्षा सूची गायब हो जाएगी. क्या पस्त हौसले वाले कर्मचारियों से नए 19 विमानों को सही सलामत रखने की उम्मीद रखनी चाहिए? यह बहुत ही अहम सवाल है. लोग तो अभी से शर्त लगाने के लिए तैयार बैठे हैं कि नए विमानों के आने से भी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.

—रमिंदर सिंह

"बिना प्रतिस्पर्धा के हम सुधर नहीं सकते. इंडियन एअरलाइंस के पास सजा या इनाम देने का कोई अधिकार नहीं"

राहुल बजाज
अध्यक्ष, इंडियन एअरलाइंस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जब भी हो ख़ुशी का मौका दीजिए सेलो का तोहफ़ा

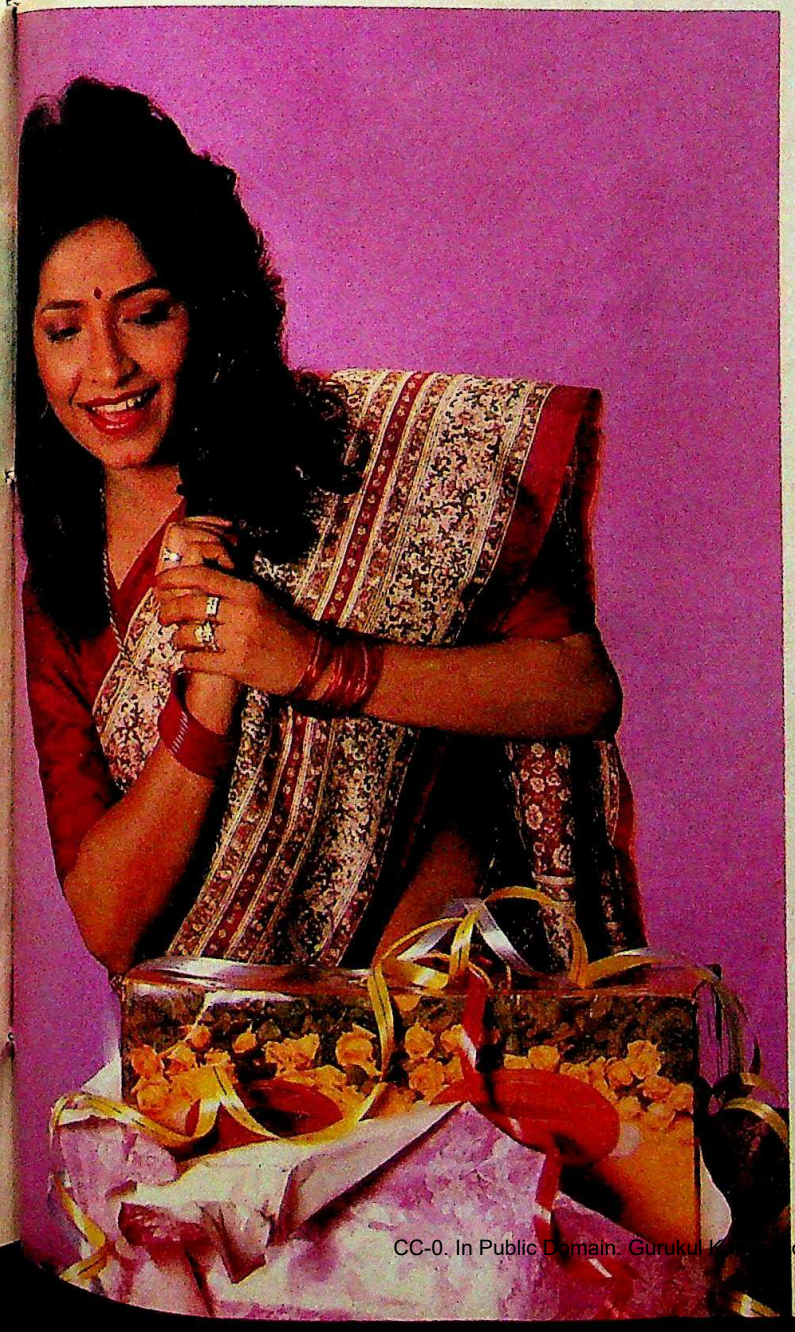

ख़ुशी का कैसा भी मौका हो, सेलो गिफ़्ट पैक सा उपहार और कोई नहीं. सेलो गिफ़्ट कलैक्शन में है एक से एक ख़ूबसूरत, और उपयोगी उत्पादनों की लम्बी कतार... कैसेरोल, लंचपैक, वॉटर-फ्लास्क, आइस-पेल, पिकनिक कैरियर... आकर्षक रंगों और डिज़ाइनों वाले इन उत्पादनों में अन्दर की ओर, बी.एस.एफ. जर्मनी के इलास्टोग्रान पॉलियूरेथेन ग्रुप से प्राप्त पॉलियूरेथेन की लाइनिंग है जो इनमें रखी हुई चीजों को घंटों ठंडा या गरम रखती है.

अब जब भी आप दोस्तों, सहयोगियों, प्रियजनों को देना चाहें कोई उपहार तो सिर्फ़ सेलो गिफ़्ट कलैक्शन से ही चुनें, ताकि सालोंसाल वे आपके इस ख़ूबसूरत तौहफ़े को इस्तेमाल करते हुए आपको हमेशा याद करते रहें.

cello®

सेलो गिफ़्ट कलैक्शन

कहीं ज़्यादा बेहतर

निर्माता : **विमको पेन कंपनी** (थरमोवेयर डिवीज़न)
११, मेहता इंडस्ट्रियल एस्टेट, आइ.बी. पटेल रोड, गोरेगांव (पूर्व),

CC-0. In Public Domain. Gurukul ... Collection, Haridwar

...ations/CP/32/88

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किशोरों का फैशन प्रेम

पश्चिमी बुखार का चढ़ता पारा

अक्सर कॉलेज छात्रों का एकाधिकार माना जाने वाला फैशन का रोग अब स्कूलों में भी प्रवेश कर गया है. देश भर के स्कूली छात्र-छात्राओं में सुंदर दिखने की जबरदस्त सनक सवार हो गई है. इनके आदर्श होते हैं रॉक सितारे. वरिष्ठ संवाददाता सिमरन भार्गव ने इस बदलते माहौल का जायजा लिया है:

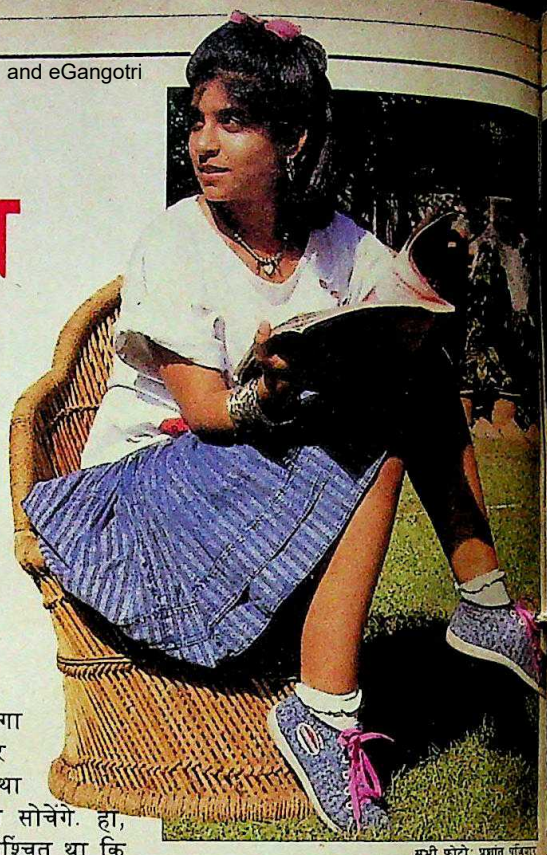

सभी फोटो: प्रशांत पांडेकर

नंदन चिंतित-सा लग रहा था. बाल घुंघराले करवाने में बहुत वक्त लग गया था. घर पहुंचने में देर हुई सो हुई, उसे स्कूल की चिंता भी सता रही थी. अध्यापकों को जब पता चलेगा कि वह स्कूल से गायब होकर बाल घुंघराले करवाने गया था तो वे उसके बारे में क्या सोचेंगे. हां, अपनी मां की तरफ से वह निश्चिंत था कि वह उसके बदले हुलिए से जरूर खुश होगी.

पर वह घर पहुंचा तो मां एकदम हैरान हो गई. वह तय नहीं कर पा रही थी कि उसका 17 वर्षीय बेटा लड़के जैसा दिख रहा है या लड़की जैसा (लेकिन नंदन खुशफहमी में था कि वह जॉर्ज माइकल जैसा लग रहा है). मां झल्ला रही थी कि इस अजूबे स्टाइल पर उसने क्यों 250 रु. बरबाद किए.

पीढ़ियों का यह अंतर आज भी बाकायदा मौजूद है पर इसमें इतनी खुशमिजाजी पहले कभी नहीं थी. आज के स्कूली बच्चे ज्यादा चुस्त और मौजमस्ती की जिंदगी जीते हैं. जितने कपड़े उनके पास हैं, उतने बाप-दादाओं ने भी नहीं देखे होंगे. रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और मैडोना की नकल करते इन स्कूली बच्चों का पसंदीदा शगल फैशन ही है. मॉडर्न स्कूल का नंदन (असल नाम नहीं) कहता है, "हम रॉक स्टारों के नक्शेकदम पर ही चलना चाहते हैं."

लड़कियां भी एकदम सुंदर दिखना चाहती हैं. मैटर डी कान्वेंट की 14 वर्षीया अनुश्री एक शालीन मध्यम वर्ग परिवार से है. मां उसके आगे सलवार-कमीजों का ढेर लगाती है पर उसे यह सब पसंद नहीं. वह कबूल करती है कि उसने मां-बाप की मर्जी के खिलाफ 45 स्कर्ट और 15 जोड़ी जूते ले लिए हैं (सात जोड़े तो उसने पिछले महीने खरीदे). कमीजों की कोई गिनती नहीं. वह हर समय सजी-संवरी रहती है.

अक्सर कॉलेज छात्रों का एकाधिकार माना जाने वाला फैशन का रोग अब स्कूलों में भी प्रवेश पा गया है; खासकर बड़े शहरों में. दसवां साल पार करने के बाद बच्चे अब बनने-संवरने पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. नतीजा भी सामने है. मॉडर्न स्कूल की हेडमास्टरनी शारदा जोगिंद्र कहती हैं, "स्कूली लड़कियों को देखें. 20 साल पहले वे सभी बेढंगी लगा करती थीं. दस साल पहले करीब आधी सुघड़ दिखती थीं. अब तो हर स्कूली लड़की सुंदर नजर आती है."

लेकिन रॉक संगीत की धुन पर नाचने

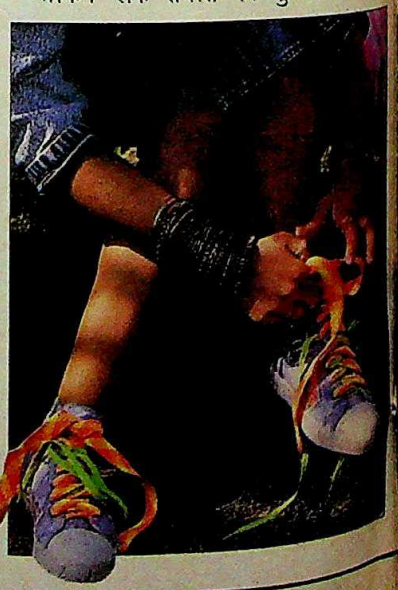

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोटो: प्रशांत पंजियार

...ी यह पीढ़ी ऊपर से नीचे तक पश्चिमी ...में रंगी है—भारतीयता से कोसों दूर. सेंट ...फ़न कॉलेज के पूर्व छात्र, 30 वर्षीय तरुण ...रीचा कहते हैं, "इन बच्चों को न्यूयॉर्क में ...दिया जाए तो ये उस माहौल में भी ...कुल फिट बैठेंगे. वे नए से नए फैशन, ...बाजी और मेलजोल बढ़ाने—सभी के ...में खासी जानकारी रखते हैं."

...रॉक संगीत के वीडिओ टेप अब बाजार में ...नेवार मिलने लगे हैं. बंबई में तो सितंबर 88 भी बिकना शुरू हो गया है. हो सकता है मां-बाप को यह सब पसंद न हो पर जैसा कि बंबई के कुंबाला हिल स्कूल की लैला नजीर कहती है, "मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे तो भारतीय संगीत कतई पसंद नहीं."

और हाल ही में राजधानी में जो मानवाधिकार रॉक शो हुआ, उसमें कई रॉक सितारों को देखने के लिए बच्चों की भीड़ जुट आई थी. वे सुबह तीन बजे तक रॉक गायकों के साथ कदमताल करते रहे. राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान में पढ़ा रहे 25 वर्षीय फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा कहते हैं, "वहां तो मुझे कुंठाओं ने घेर लिया. मैंने इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे थे. उनकी जीवंतता देख मैं खुद को बूढ़ा महसूस करने लगा हूं."

नई और पुरानी पीढ़ी में स्कर्ट की लंबाई को लेकर कभी इतना विवाद नहीं उठा होगा. स्कर्टों की दिनोदिन घटती लंबाई ने मां-बाप के चेहरे लटका दिए हैं. 16 साल की दिव्या दीवान को मिनी स्कर्ट पहनने की इजाजत नहीं है. इसका निदान भी उसने ढूंढ़ निकाला है. वह घर से सलवार-कमीज में निकलती है लेकिन कार में बैठते ही टॉप और मिनी स्कर्ट पहन लेती है.

और लड़के? उनका तो फैशन से दूर का भी वास्ता नहीं हुआ करता था. लेकिन जैसा कि इंदौर के एक सज्जन कहते हैं, "मैं सचमुच देखता हूं कि आज के लड़के फैशन में लड़कियों से कहीं आगे हैं." वे माइकल जैक्सन जैसी पतलूनें पहनते हैं—यानी टखनों से कुछेक इंच ऊंची जिनसे उसकी रंगीन जुराबें झांकती रहती हैं. कमीज भी उसी की तरह ढीली-ढाली, जिसमें जितना ज्यादा कपड़ा लगा हो, उतनी ही अच्छी मानी जाती है.

पार्टियों में तो लड़कियां स्कर्ट या जीन्स पर बित्ते भर के टॉप पहनना ही पसंद करती हैं. यानी थोड़ा भी हाथ ऊपर उठे तो मैडोना की तरह जिस्म की एक झलक एकदम सामने वाले को मिल जाए.

16 साल की आयशा ने मैडोना जैसी

प्रमोद पुष्करणा

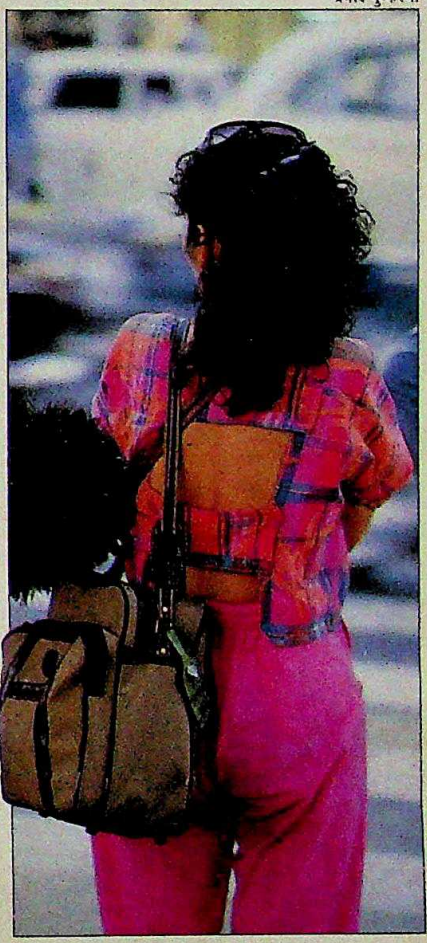

बनने की धुन में अपने बालों को ही ब्लीच करवा लिया. वह घर लौटी तो उसके पिता ने अपना सिर धुन लिया. आखिर बाप-बेटी में समझौता हुआ कि आगे से आयशा बालों को ब्लीच करवाने के बजाय हिना ही लगवाएगी, भले ही उसके बाल लाल हो जाएं. 16 साल की दिव्या बंबई में रहती है. एक दिन वह भी बालों को घुंघराले करवाकर घर लौटी और फिर दिन भर अपनी दादी मां से बचती फिरती रही, जो स्कूल भेजने से पहले उसके बालों में तेल चुपड़ना चाहती थी. रोक्सेन अभी 12 साल की ही है लेकिन अपने बालों की स्टाइल वह अभिनेत्री ब्रुक शील्ड्स की तरह रखना चाहती है.

लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि स्कूली लड़कियों के बस्तों में किताबों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लीडर की गारंटी

नकल से दुहरी सुरक्षा

हरचंद कोशिशों के बावजूद हम ड्यूरोबोर्ड की नकल एकदम रोकने में सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हमने प्रत्येक ड्यूरोबोर्ड पर आपके जाने-पहचाने लेबल के साथ एक स्ट्रिप भी लगा दी है। ध्यान दीजिये कि आप जो ड्यूरोबोर्ड खरीद रहे हैं उस पर वे दोनों है।

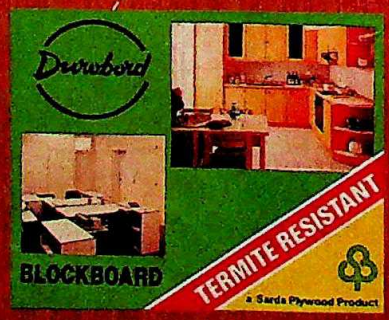

Durobord™

असली नं - १

ड्यूरो-
ब्लॉकबोर्ड का दीये

सारदा प्लाइवुड
इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
वर्क्स: जेपुर (आसाम)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के साथ-साथ मेकअप का सामान भी जगह बनाता जा रहा है. आठवीं क्लास की कई लड़कियां भी फाउंडेशन और लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं. शारदा जोगिंद्र कहती हैं, "मुझे पता होता है कि लड़कियों ने आंखों में नीले रंग का आई लाइनर और गुलाबी आईशैडो लगा रखा है."

बड़ों को यह सब भले ही बेतुका लगे पर इन बच्चियों का मानना है कि आज जमाना इसी का है. 'बेतरतीब' नजर आने के लिए वे बड़ी सावधानी से अपने कपड़े और गहने चुनती हैं. कानों की बालियां बड़ी और लटकती हुई होनी चाहिएं. गले में भले ही कुछ न हो पर जरा-से कान में सात-सात मुंदकियां पहन सकती हैं. घड़ी भी सीको के बजाय स्वाच की ही ठीक रहेगी. जूते नाइक के मुकाबले रीबॉक के बेहतर दिखेंगे. और अगर एकदम ही आधुनिक बनना है तो रे बेन के गॉगल्स जरूरी हैं.

जूते भी कपड़ों के साथ मैच करते होने चाहिएं, हालांकि दूसरे रंग भी चलेंगे. और जो ड्रेस एक बार दोस्त मंडली के सामने पहन चुकी हैं, उसे दोबारा पहनने से तौबा है. किसी पार्टी में जो ड्रेस एक बार पहन ली जाए, वह दोबारा तो मानो क्लब या सिनेमा जाने जैसी छोटी-मोटी जगहों के लिए ही सुरक्षित हो जाती है. लेकॉस्टे और पोलो टी-शर्ट तो अब 'आउट ऑफ डेट' हो चुकी हैं जिन्हें मातमपुर्सी के वक्त ही पहना जा सकता है. स्कूल की यूनिफार्म में भी थोड़ा फेरबदल करवाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए दरजी की मुट्ठी थोड़ी गरमानी होगी.

और जिस भी बच्चे के परिवार का कोई सदस्य विदेश आता-जाता रहता है, वह तो कुछ 'निहायत जरूरी' सामान उससे मंगवाता ही है. जमाने के साथ-साथ चलना बहुत आसान है. शारदा जोगिंद्र कहती हैं, " बच्चों के फैशन करने में मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती, बशर्ते कि वह बहुत भड़कीला न हो और उनकी पढ़ाई का हर्जा न हो." बच्चों के प्रति अध्यापकों के रवैये में भी अब बहुत बदलाव आ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि बच्चे फैशन में जितना आगे हैं, पढ़ाई में उससे भी ज्यादा तेज. मॉडर्न स्कूल के छात्रों को याद है कि एक जमाना था जब किसी लड़की को भौंहे बनवाने के 'अपराध' में पूरे स्कूल के सामने चांटे लगाए जाते थे. वर्मा कहते हैं, "बच्चों की इस पीढ़ी की उपेक्षा नहीं की जा सकती. आत्मविश्वास से भरपूर इन बच्चों को इस बात का जरा भी रंज नहीं कि वे अभी से पार्टी, डिस्को में जाते हैं."

सचमुच आज के बच्चे बहुत बदल चुके हैं. वे जानते हैं उन्हें क्या चाहिए. माता-पिता के बिना अकेले ही वे विदेश यात्रा कर आते हैं. प्रेमक्रीड़ा भी कच्ची उम्र में ही शुरू हो जाती है. अपनी बात मनवाने के लिए वे मां-बाप से बहस कर सकते हैं, उन्हें झांसा दे सकते हैं, उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं. कैथेड्रल स्कूल के एक पूर्व छात्र बताते हैं, "जब हमें स्कूल की तरफ से घुमाने ले जाया जाता था तो बस में लड़कियां एक तरफ बैठतीं और लड़के दूसरी तरफ. दोनों एक-दूसरे पर कागज के गोले बनाकर फेंकते थे. आज सहशिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई है."

इस मौजमस्ती और फैशन की शुरुआत नवीं कक्षा से हो जाती है. इसी समय कंघे-शीशे स्कूल के बस्तों में जगह पाने लगते हैं और डांस पार्टियों का दौर शुरू होता है. किसी का हो जाने की और प्रशंसाभरी नजरें बटोरने की ख्वाहिश इस उम्र में बहुत ज्यादा होती है. लेकिन अब चेहरे की बजाय कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है. नंदन मानता है, "जब मैं किसी लड़की की ओर ताकता हूं तो पहले मेरा ध्यान उसके कपड़ों की ओर जाता है, फिर चेहरे की ओर." उसका 16 वर्षीय दोस्त अमर भी कहता है, "पसंदीदा लड़की हो, पसंदीदा खेल और पसंदीदा संगीत—यही जिंदगी है."

और स्कूली बच्चों के फैशन की मांग पूरी करने के लिए एक पूरा ढांचा ही तैयार हो गया है. यह व्यवसाय खूब फल-फूल रहा है. 'इंटरशॉप' के विजय मेहता तो फैशन के नए नमूने खोज निकालने के लिए अपने डिजाइनिंग टल को नियमित रूप से बाहर भेजते रहते हैं. 'मिसचीफ' और 'रूट्स' जैसे बुटीक में तो यहां तैयार नवीनतम डिजाइनों के कपड़े मिलते ही हैं. लेने वालों के लिए तस्करी का माल भी मौजूद है. स्वाच घड़ी 600 रु. में, नाइक जूते 700 रु. में और जीन्स 500 रु. या इससे अधिक में.

लेकिन कम बजट में आधुनिक से आधुनिक कपड़े मुहैया कराने का श्रेय निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों से बचे-खुचे माल को ही है. दिल्ली के जनपथ और बंबई के फैशन स्ट्रीट में फुटपाथ पर लगने वाले बाजारों में सूती पैंट 75 रु., कमीज 25 रु., और स्कर्ट 30 रु. में मिल जाती है. वस्त्र निर्यातक रवि सिंह कहते हैं, "फैशन के मामले में भारत यूरोप से आगे नहीं तो उसके हमराह जरूर है, वह भी वहां के मुकाबले पचासवां हिस्सा कीमत पर."

आगे सीजन में स्कूली बच्चों में कौन-सा फैशन लोकप्रिय होगा? डिजाइनरों का कहना है कि भारतीय चटख रंगों का ही बोलबाला रहेगा—हरा, संतरी, गहरा गुलाबी और पीला. स्कर्टों की लंबाई अभी और घटेगी. स्टोन, स्नो और एसिड वाश्ड जीन्स गायब होती जा रही हैं और उनकी जगह सादा डेनिस फिर से लोकप्रिय हो रहा है. काले रंग की जीन्स और निओन टी-शर्ट के प्रचलन की भी संभावना है. लेकिन जोशीले युवाओं के फैशन की इस दुनिया में कुछ भी भारतीय नहीं है. कम-से-कम इनकी नजर में तो पश्चिम से बढ़कर जैसे कुछ है ही नहीं.

पसंदीदा वस्त्रों की खरीदारी

प्रमोद पुष्करणा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिओल ओलंपिक

आयोजन से बढ़ी शान

दक्षिण कोरिया द्वारा अपनी क्षमताओं का बेमिसाल प्रदर्शन

अगस्त की रातों में चमकने वाले चांद के स्वागत में या फसलों के उत्सव चु' सोक पर कोरियाई लोग 'कांगंगसुवाले' नामक नृत्य किया करते हैं. इसमें नृत्य का अगुआ किसी गीत की एक पंक्ति उठाता है और उसे घेरकर नाच रहे लोग उसे दोहराते हैं. धीरे-धीरे ताल तेज होने लगता है, पैरों की गति तेज हो जाती है और संगीत का लय भी. और एक विचित्र समां बंध जाता है.

पिछले पखवाड़े साल का यह सबसे महत्व-पूर्ण पर्व जब फिर आया तो कोरिया की पुरानी राजधानी में 'कांगंगसुवाले' नृत्य के आयोजन बड़े पैमाने पर और जोर-शोर से हुए. हन नदी के किनारे, चाक्शिल और समुद्रतटीय शहर पुसान के 27 केंद्रों पर यौवन अपने पूरे निखार पर था.

ओलंपिक ने विजेता और विजित बनाए, सितारे और घोटाले दिखाए, गौरव और शर्म के क्षण पैदा किए. लेकिन 4 करोड़ कोरि-याइयों ने साबित कर दिया कि असली गौरव के हकदार सिर्फ वे ही हैं. 1950 के दशक में बंटवारे की लड़ाई के बाद ओलंपिक ही उनके लिए महत्वपूर्ण घटना थी. यह उनके लिए इतना खास मामला था कि 20,000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने आयोजकों के साथ दिन-रात एक कर दिया और एक भी पैसा नहीं लिया. झुकी कमर, जोड़ों के दर्द से पीड़ित और 80 के ऊपर पहुंच गई महिलाएं भी विदेशियों को देखकर अपनी कुर्सी छोड़-कर उठ जाती थीं और जोर देती थीं कि मेहमान उनकी कुर्सी पर बैठें.

अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार के डर, आतंक-वादियों की धमकी और अंदरूनी राजनैतिक हलचल को कोरियाइयों ने इस आयोजन में बाधा बनने नहीं दिया. और अब वे इसकी सफलता पर सीना ताने दुनिया को विश्व-बंधुत्व और समरसता के अपने दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं. वैसे, उनका यह दर्शन उनके अपने बंटवारे के संदर्भ में मदद करता नहीं दिखता. निकट भविष्य में दोनों हिस्सों के मेलमिलाप की कोई संभावना नजर नहीं आती. फिर भी, इस आयोजन ने कोरियाई लोगों में आत्मसम्मान और गौरव का भाव जगाया है. साथ ही उनमें राष्ट्रीय चेतना की नई लहर पैदा हुई है. ऐसे में कोरिया द्वारा

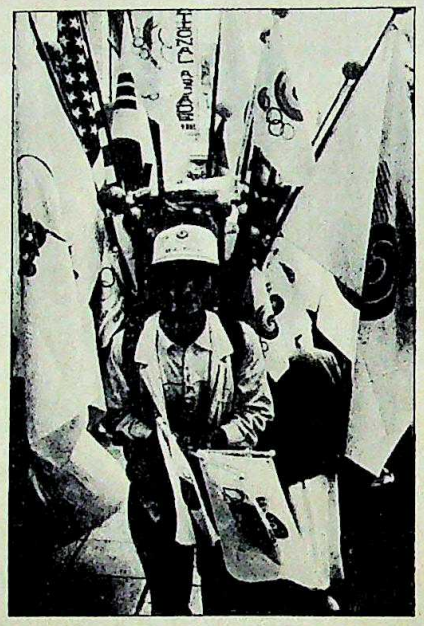

■ विभिन्न देशों के झंडों की बिक्री

इस ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक पदक बटोरने पर आश्चर्य नहीं होता. साथ ही इस आयोजन के उत्साह ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री रो तई बू के खिलाफ फैल रही नाराजगी को भी दबा दिया. दुनिया को कुछ कर दिखाने के उत्साह के आगे दूसरी सभी बातें गौण हो गई थी कोरियाई लोगों के लिए. इन तमाम बातों से यह साफ साफ साबित होता है कि कोरियाई लोग इस आयोजन के जरिये अपनी औद्योगिक और आर्थिक क्षमता का एहसास दुनिया को करा देना चाहते थे.

इस शताब्दी के शुरू के 35 वर्ष तक जापान का उपनिवेश रहे और पचास के दशक में लंबी अंतरराष्ट्रीय लड़ाई का केंद्र रह चुके इस देश के लिए यह ओलंपिक दुनिया को यह जताने का अच्छा साधन बना कि वे तमाम सदमों से उबर गए हैं और यह कि वह उन्हें गुलाम बनाने वाले देशों को भी चुनौती देने की हैसियत में पहुंच गया है. कोरियाई खिलाड़ियों को तब सबसे अधिक खुशी होती थी जब वे किसी जापानी को पछाड़ते थे. और

■ सिओल में बना पत्रकार नगर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

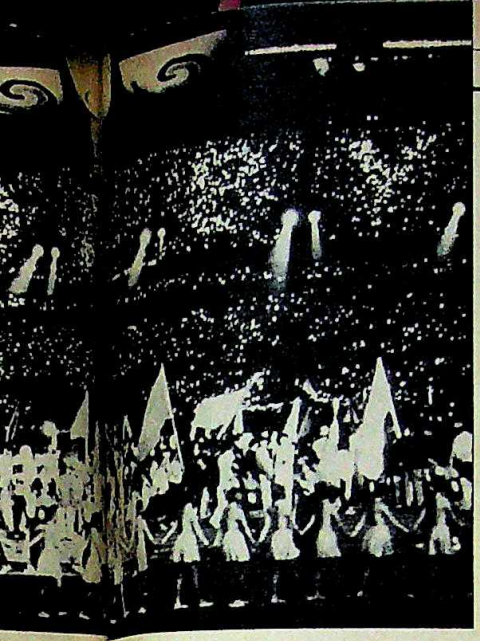

■ खेलों का रंगारंग समापन समारोह

...ह के आगे
...ी कोरियाई
...से यह साफ
...ई लोग इस
...द्योगिक और
...या को करा

...5 वर्ष तक
...र पचास के
...ई का केंद्र रह
...पिक दुनिया
...बना कि वे
...र यह कि वह
...भी चुनौती
...है. कोरियाई
...खुशी होती
...ड़ते थे. और

...र

...कमाई कम हुई तो कोई खास बात नहीं है. उनका मानना है कि अभी बाहर जाने वाला कोरियाई माल जो नाम कमाएगा उससे उनका आगे का व्यापार बढ़ेगा.

लेकिन व्यापारियों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी. ह्युंदाई, दायवू, सैम्संग, गोल्डस्टार जैसे बड़े व्यावसायिक घरानों ने, जिन्होंने कोरियाई अर्थव्यवस्था को इतना आगे पहुंचाया है, इस ओलंपिक के जरिये अपना प्रचार कराने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया. सिओल में एक पश्चिमी देश के दूतावास के व्यावसायिक सहायक ने कहा, "कोरियाई निर्माताओं को दुनिया भर में एकाएक नाम मिला है. जल्दी ही यहां के निर्यात में एक और उफान आएगा."

खेल गांव और पत्रकारों के ठहरने के कमरों सहित सभी सेवाओं के लिए ओलंपिक आयोजन समिति ने भाड़ा लिया. एक कमरे का भाड़ा प्रतिदिन 942 रु. था. लेकिन यह खर्च विभिन्न प्रायोजकों ने उठाया. वहां लगे टीवी सेट गोल्डस्टार के थे और फ्रिज सैम्संग के. खरीदारी वाले बैग, साबुन और उपहार में दी जा रही कोलोन की बोतलों पर भी कंपनियों के निशान थे तथा लिखा था '24वें ओलंपिक के लिए अधिकृत आपूर्तिकर्ता'. जिंडों फर्स, केआईए मोटर्स और पैसिफिक केमिकल्स जैसी कंपनियों ने खिलाड़ियों और पत्रकारों को अपनी फैक्टरियों में घुमाने की व्यवस्था भी की थी. उन्होंने इसके लिए जो आकर्षक निमंत्रण कार्ड छापे थे, उन पर लिखा होता था, 'मुफ्त उपहार, भोजन और शराब' उपलब्ध होगी.

ऐसे व्यावसायिक माहौल में आयोजन समिति की ओर से मिला परिचयपत्र— 'डॉग टैग'—तो जैसे विशिष्ट हैसियत का प्रमाण-पत्र-सा बन गया था. चार प्रमुख खेल सामग्री निर्माता कंपनियों ने खेल गांव के पास अपने सेवा केंद्र बनाए थे जिनमें खिलाड़ी अपना कार्ड दिखाकर कोई भी चीज मुफ्त ले सकते थे—ट्रैक शूट से लेकर जूते, क्रोनोमीटर से लेकर फिंगर प्रेसर मसाज तक. लेकिन अधिकारियों और पत्रकारों को बैग, टोपी, पेन, टी-शर्ट और चाबी के गुच्छे वगैरह से ही संतोष करना पड़ा.

और इस मुफ्तखोरी का रंग भी गजब चढ़ा. विदेशियों को आकर्षित करने का यही सबसे बढ़िया तरीका रह गया था. एडिडास, नाइक, एसिक्स और कोरियाई खेल सामग्री कंपनी 'ले कैफ' ने तो ऐसे क्लब ही खोल रखे थे जहां 'सम्माननीय' अतिथि जाकर कुछ खाते-पीते हुए आराम से गप्प कर सकें. ये सारे क्लब शाम सात बजते ही भर जाते थे. यह मुफ्तखोरी अंतिम दिनों में सबसे अधिक बढ़ गई. ओलंपिक पार्क और खेल परिसर के बीच के इमैन्युएल गिरिजाघर ने एक बैनर लगाया, "प्रभु यीशु का संदेश सुनने आइए. हमारे यहां रात का भोजन कराने की भी व्यवस्था है."

■ खेल सामग्रियों की प्रदर्शनी

मुफ्तखोरी कराने की यह प्रतिद्वंद्विता दरअसल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए थी. कोडक ने खेल के मुख्य प्रयोजक होने का गौरव 'कई करोड़ डॉलर' (एक सूत्र के अनुसार) में हासिल किया था. इसने भी अपना एक केंद्र लगाया था जहां मान्यताप्राप्त फोटोग्राफरों को फिल्में, प्रोसेसिंग की सुविधा और फ्लैक जैकेट मुफ्त दी जाती थी. खेलों के दौरान कोडक ने मुफ्त में 1,10,000 फिल्में बांटी, 38 लाख रंगीन फोटो और 60,000 श्वेत-श्याम तस्वीरें तैयार की. इसी तरह कैमरे की अधिकृत सप्लायर 'निकॉन' ने भी फोटोग्राफरों को मुफ्त बैग बांटे. निकॉन और कोडक की मुख्य प्रतिद्वंद्वी कंपनियां, कैनन और फुजी भी पीछे नहीं रहीं. उन्होंने भी

...खेलों का रंगारंग समापन समारोह

...बला जूडो का हो तो कहना ही क्या.

जीतने की उनकी धुन की तुलना सुरक्षा की सनक से ही की जा सकती थी. सभी स्टेडियमों, खेल गांव, पत्रकारों के ठहरने की जगह और होटलों के प्रवेश द्वार पर भी मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे. वहां आने वाली सभी कारों की जांच होती थी और अल्सेशियन कुत्तों का पहरा होता था. लेकिन सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था खेल गांव पर थी. वहां के सभी दरवाजों पर अत्याधुनिक उपकरण लगे थे तथा ऐसे दक्ष कमांडो तैनात थे जो बिना हथियार के ही किसी को मार सकने की क्षमता रखते हैं.

भारत की तरह यहां भी सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था उचित थी. और मजेदार यह कि यह सारा कुछ भारत के नामी पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार की देखरेख में हो रहा था. नौकरी से अवकाश पाने के बाद से कुमार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बहुत सक्रिय सदस्यों में से हैं. लेकिन सुरक्षा के मामलों में भारत की ही तरह अति भी कर दी गई थी. खेलों के शुरू होने के पहले ही यहां चले कमांडो प्रशिक्षण की तस्वीरें दुनिया भर में छप गईं. कहा जा रहा है कि इस कारण भी विदेशों से लोग उतनी बड़ी संख्या में नहीं आए. खेल शुरू होने से एक पखवाड़े पहले भी सिओल के किसी होटल में एक कमरा पा जाना असंभव था. लेकिन बाद में जब बुकिंग कराने के बाद भी अनेक विदेशी नहीं आए तो होटल वाले रियायत भी देने लगे. सिओल ओलंपिक आयोजन समिति के लिए यही चीज सांत्वना देने वाली थी कि सुरक्षा प्रबंध पक्के रहे. व्यापारियों का कहना है कि अगर विदेशियों के कम आने से उनकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG

प्रेस सेंटर के सामने ऐसी ही मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई.

अंतरराष्ट्रीय खेल पत्रकार संघ ने सिओल के सात सितारा होटल लॉट्टे इंटरनेशनल में सबसे पहले पहुंचने वाले 1000 पत्रकारों के लिए एक भोज और उपहार का आयोजन किया. भोज का खर्च कई कंपनियों ने उठाया. यह भोज शाम आठ बजे से होना था लेकिन सात बजे तक ही दो हजार से अधिक पत्रकार पहुंच गए. फिर तो दो बोतल शराब और एक टी-शर्ट वाले उपहार के थैलों की लूट मच गई.

हां, मुफ्तखोरी में थोड़ी झिझक सिर्फ एक

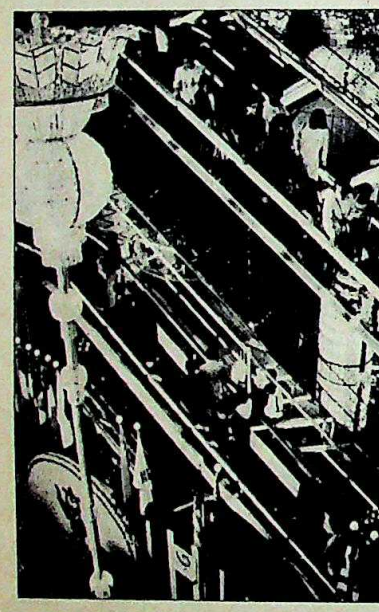

■ होटल लॉट्टे का डिपार्टमेंटल स्टोर

ही जगह दिखाई जाती थी. जब यही पत्रकार, खिलाड़ी और अधिकारी ओलंपिक गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते थे तो वहां की रिसेप्सनिस्ट के पास ही खुली ट्रे में कंडोम का ढेर रखा होता था. इसके नीचे लिखा था, "जरूरत हो तो जरूर ले जाइए." पत्रकार गांव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, "कोई भी हमसे इनकी मांग नहीं करता लेकिन डिब्बे का डिब्बा माल मिनटों में खत्म हो जाता." यह बताने की जरूरत नहीं है कि कंडोम रोजेटैक्स कंपनी ने मुफ्त दिए थे.

कोरियाई लोगों ने एक-एक चीज का ख्याल रखा था. विदेशी पत्रकारों के लिए शिकायत का कोई मौका ही न था. समाचार माध्यमों के लिए भी यह ओलंपिक सबसे बड़ी घटना थी. खेलों में भाग लेने आए खिलाड़ियों की संख्या 13000 ही रही

■ भारतीय बच्चों के पुरस्कृत चित्र

जबकि पत्रकारों की संख्या 15000 हो गई थी. और फिर भी उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा. वैसे कुछ ऐसी मुश्किलें थीं जिनका निदान कर पाना संभव भी नहीं था.

वर्षों की मेहनत के बाद भी अंग्रेजी बोलने वाले कोरियाई थोड़े ही थे. पिछले तीन महीनों से सिओल के टैक्सी-चालकों को भी रोज घंटे भर अंग्रेजी सिखाई जाती थी लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ. बाद में आयोजकों ने जगहों के नाम वाले कार्ड बांटे जिन्हें दिखाने पर टैक्सीचालक उपयुक्त जगह तक पहुंचा दें. यह मुश्किल तब भी बनी रही जबकि सरकार ने पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे कोरियाई छात्रों को भी बुला लेने की कोशिश की थी. अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दर्जनों छात्र रोज प्रेस विज्ञप्तियां और दूसरी टिप्पणियां तैयार करते थे.

इस आयोजन के माध्यम से कोरियाइयों ने कुछ नए राजनयिक समीकरण भी बनाए. कोरियाई बच्चों के हाथों में सोवियत संघ का झंडा दिखना कुछ अजीब लगता था और बॉक्सिंग के एक मुकाबले के विवाद में 35 वर्ष पुराने कोरिया-अमेरिका के घनिष्ठ संबंधो को भी लोग भूल गए. कोरियाई लोग पूर्वी खेमे के देशों की खूब प्रशंसा करते रहे. ओलंपिक के दौरान ही यहां हंगरी का वाणिज्य दूतावास खुलने से यह सिद्ध हो गया. अमेरिका का प्रदर्शन अच्छा न होने पर कोरियाइयों को खास दुख नहीं हुआ लेकिन एशिया, खासकर भारत के खराब प्रदर्शन पर कइयों को अफसोस हुआ.

कोरियाई लोगों के मन में भारत के लिए खास स्नेह है. पचास के दशक में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में गए जनरल थिमैय्या के नेतृत्व वाली भारतीय सेना के अच्छे व्यवहार के कारण ही यह स्नेह बना है. कोरिया के पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत में मिली भारतीय मदद को भी वे भूले नहीं हैं. लेकिन उन्हें सबसे अधिक याद है कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर की वे कविताएं, जो उन्होंने खास तौर से कोरियाइयों को जापानी उपनिवेशवाद से लड़ने को प्रेरित करने के लिए लिखी थी.

ऐसे में एक कोरियाई छात्रा ने भारत के खराब प्रदर्शन के बाद 'इंडिया टुडे' को वह नजारा दिखाया जो भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ाता है. उस लड़की ने स्नेह से कहा, "आपके देश ने इतने स्वर्णपदक जीते हैं और आपको पता ही नहीं है?" ये स्वर्ण-पदक खेल के मैदान से नहीं, चित्र प्रति-योगिता में बटोरे गए थे. भव्य कोरियाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास के एक हॉल में दुनिया भर के बच्चों द्वारा बनाए गए सैकड़ों चित्र लगे थे. जिन 21 गैर-कोरियाई बच्चों को चित्रकारी के लिए स्वर्णपदक दिया गया उनमें से 10 बच्चे भारतीय थे. 24वें ओलंपिक में भारत की यही पक्की जीत थी.

यही नहीं, अधिकांश विजेता बच्चे बंगाल के ही थे जिसे कोरियाई लोग रवि बाबू के कारण अधिक अच्छी तरह जानते हैं. आज भी कोरियाई अखबारों में संपादकीय की शुरुआत अक्सर रवि बाबू की पंक्तियों से की जाती है. उनके गीत वहां के स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग बन चुके हैं. 1928 की अपनी जापान यात्रा के समय रवि बाबू ने लिखा था, "एशिया के स्वर्णयुग में कोरिया ही प्रकाश स्तंभ था. आज पूरब में रोशनी के लिए इस प्रकाश स्तंभ को प्रज्वलित करने की जरूरत है." आज आम कोरियाई रवि बाबू की ये पंक्तियां बड़े गर्व से दोहराता है और ओलंपिक मशाल की ओर संकेत करता है.

—शेखर गुप्ता, सिओल में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रानावि

एक और पटाक्षेप

निदेशक के इस्तीफे से संकट

चार अक्तूबर के दिन जिस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रबंध समिति संस्थान की बदहाली पर विचार करने और यह तय करने में जुटी हुई थी कि निदेशक रतन थियम का इस्तीफा मंजूर किया जाए या नहीं, उस समय पांच किलोमीटर दूर अपने किराए वाले घर में थियम अपना बोरिया-बिस्तर बांध रहे थे.

मंडूकों के लिए अपने इंफाल वाले घर के बारे की चिपकियां लिखते हुए उनका कहना था, "अठारह महीने तक इस संस्थान का निदेशक रहने के बाद आज मैं दावे से कह सकता हूं कि भगवान भी उतर कर रानावि को चलाने आ जाए तो वह इसे नहीं चला पाएगा. कोई इज्जतदार रंगकर्मी इस पद पर आने से पहले हजार बार सोचेगा."

उधर नाटकों की मायानगरी बहावलपुर हाउस में बैठी समिति भी फैसला कर चुकी थी कि थियम का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए. और इसके साथ ही पिछले कई महीनों से रानावि में चलते आ रहे उस लंबे नाटक का परदा गिर गया जो न तो अपनी तरह का पहला था और न जिसे आखिरी मानने का जोखिम उठाया जा सकता है. स्क्रिप्ट के थोड़े बहुत बदलाव के साथ पिछले 30 साल के दौरान यही नाटक इब्राहीम अलकाजी, ब.व. कारंथ और मोहन महर्षि जैसे दिग्गजों के साथ भी खेला जा चुका है. इस बार नाटक का परदा गिरने से पहले मात्र 60 विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में छह हड़तालें हुईं, दर्जनों प्रदर्शन हुए और भूख हड़ताल तथा घेराव जैसे कदम उठाए गए. सिर्फ इतना ही नहीं, रानावि के इतिहास में पहली बार अध्यापकों ने भी निदेशक के खिलाफ हड़ताल की, मोर्चे लगाए और उसे हटाने के लिए प्रचार अभियान चलाया.

अभिनय के प्रोफेसर रामगोपाल बजाज के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान थियम पर जो आरोप लगाए गए उनमें प्रमुख यह था कि अपने कार्यकाल के दौरान वे विदेश यात्राओं और रानावि से बाहर घूमने में ही अधिक व्यस्त रहे. इन आरोपों के जवाब में थियम का कहना था कि, "मेरे खिलाफ अभियान चलाने वाले इसलिए बढ़-चढ़ कर बोल रहे हैं ताकि

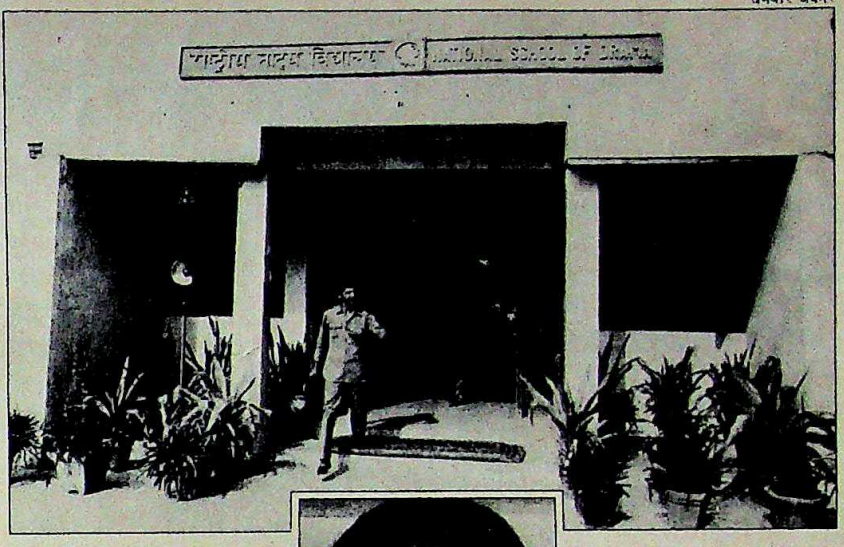

धर्मवीर जयनर

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भवन और (बाएं) रतन थियम: बेआबरू होकर निकले

अपनी करतूतों से लोगों का ध्यान बंटा सकें. जिनकी पढ़ाने की बजाय अन्य कार्यों में रूचि हो, उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए." जहां तक देश के भीतर कहीं आने-जाने की बात है इस बारे में उनका दावा है कि ये यात्राएं रानावि के निदेशक की हैसियत से की जानी जरूरी थीं. और विदेश यात्राओं के बारे में उनकी सफाई यह है कि निदेशक बनने से पहले जो वादे उन्होंने विभिन्न संस्थाओं से किए थे उनमें से कुछ को पूरा करना बहुत जरूरी था. वे कहते हैं, "दो साल की नौकरी के बाद भी तो मुझे रंगमंच की दुनिया में ही बने रहना है."

रानावि में मौजूदा असंतोष की जड़ें इतिहास में बहुत दूर तक फैली हैं. यहां के चलने वाले तदर्थवाद का आलम यह है कि 30 साल बीतने के बाद भी अब तक एक मानक पाठ्यक्रम तैयार नहीं हो पाया है. देश का एकमात्र रंग संस्थान होते हुए भी विद्यालय के पास अपना ऐसा प्रेक्षागृह नहीं है जहां विद्यार्थियों को सही ढंग से अभिनय, मंच-सज्जा और रोशनी आदि का प्रशिक्षण दिया जा सके. रंगकर्म के लगभग 20 क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए यहां केवल 10 अध्यापक हैं और काम चलाने के लिए बाहर से कुछ लोगों को ठेके पर कुछ समय के लिए बुलाया जाता है. और आवासीय संस्थान होते हुए भी न तो यहां छात्रों के लिए सही छात्रावास है और न अध्यापकों के लिए आवास. इन हालात में अगर विद्यालय में असंतोष बना रहे तो हैरानी कैसी?

अपने मूल उद्देश्यों से भटके हुए रानावि के बारे में वरिष्ठ नाट्य समीक्षक और एक जमाने में वहां निदेशक रह चुके नेमिचंद्र जैन दुख जाहिर करते हैं और कहते हैं, "यहां कभी भी छात्रों के प्रशिक्षण और नाटक प्रदर्शन के बीच सही संतुलन बनाकर नहीं रखा गया. प्रदर्शनों पर ज्यादा ध्यान देने से भले ही कुछ निदेशकों को देश-विदेश में वाहवाही मिली हो पर इस कारण प्रशिक्षण गौण बनकर रह गया और विद्यार्थियों में कुंठा पैदा हुई."

इन सब स्थितियों को देखते हुए अब समिति और मंत्रालय स्तर पर इस सवाल ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया है कि क्या निदेशक पद केवल रंगकर्मियों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए? विख्यात रंगकर्मी, फिल्मकार, समिति के सदस्य और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष गिरीश कर्नाड कहते हैं, "इसे एक स्वायत्त संस्थान बनाने का फैसला ही गलत था. ऐसे संस्थान को चलाने के लिए किसी कलाकार के बजाय कला की समझ वाला प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए."

थियम के बाद रानावि में कांटों का ताज किसे पहनाया जाएगा यह तो समय आने पर ही पता चलेगा, पर जिस तरह एक के बाद एक नामी-गिरामी निदेशक को रानावि से बेआबरू होकर निकलना पड़ा है उसे देखते हुए रंगकर्मियों की बिरादरी में ताजा सवाल यही घूम रहा है कि काठ के इस मरियल घोड़े पर कौन बैठने का साहस करेगा?

—विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चित्रकला

नए कलाकारों का जमाना

कला बाजार की स्थिति और विषयवस्तु में बदलाव

कला की दौड़ में अब छुपे रुस्तम अपना पांव आगे बढ़ाने लगे हैं. हाल तक सिर्फ जमे-जमाए लोगों की ही पूछ हुआ करती थी और उन्हीं पर दांव लगते थे. लेकिन आज कठिन साधना के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सफलता के सोपान चढ़ने लगी है.

इस नई पीढ़ी में कुछ तो कला स्कूलों से अभी-अभी निकले कलाकार हैं. इनकी कलाकृतियां अच्छी-खासी बिकने लगी हैं और चर्चा का विषय भी बन रही हैं. कला जगत के नए संचालक और बंबई की तेजी से विकास कर रही गैलरी 7 (सालाना कारोबार: एक करोड़ रु.) के निदेशक अरुण सचदेव कहते हैं, "नामी-गिरामी और पुरानी पीढ़ी के कलाकार आत्मतुष्ट हो गए थे. उनमें कोई गतिशीलता नहीं रह गई थी. वे पुरानी प्रतिष्ठा के सहारे ही जिंदा थे. लेकिन अर्पिता सिंह, शीला गौडा, पुष्पमाला, नवतोज, बी.वी. सुरेश सरीखे कलाकारों ने वाकई सनसनी मचा दी है. उनकी कृतियां लोगों की नजरों में चढ़ गई हैं."

भारत में कला की खस्ताहाल दुनिया में अब कुछ नई और अद्भुत घटनाएं होने लगी हैं. यह जमाना अब तक अज्ञात रहे कलाकारों का है. वे देश के हर कोने से उभर रहे हैं. मजेदार बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत के हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से पहले बड़ोदा स्कूल में रह चुके हैं. सबकी सूची बनाना तो मुश्किल है ही, उनमें से कुछ को चुनना तो और भी कठिन मामला है.

लेकिन बंबई की प्रतिभाशाली चित्रकार नवजोत को ही लीजिए. बंबई के बाहर और कला जगत में भी कम ही लोग उनसे परिचित हैं. इस दायरे से बाहर का तो शायद ही कोई उन्हें जानता हो. पर भारत में क्रिस्टी की प्रसिद्ध नीलामी के दौरान कला जगत के सभी बड़े नाम पीछे छूट गए और उनकी कलाकृति 85,000 रु. में बिकी. मजदूर वर्ग के बच्चों की दुनिया के बारे में बिंदु चित्रण शैली में उनकी बनाई कलाकृतियां जब बंबई की गैलरी 7 में प्रदर्शित हुईं तो उनके तैल-चित्र पहले ही दिन बिक गए.

फिर, दिल्ली की अपने में ही खोई रहने वाली चित्रकार अर्पिता सिंह हैं. वे बड़ी मेहनत से काम करती हैं. कई साल तक उनकी पहचान नहीं बन पाई. अब उनका नाम कलाकारों की अगली पंक्ति में आ गया है. कला-मर्मज्ञों के बीच उनका नाम दबी जुबान से लिया जाता है. प्रदर्शनियों के दौरान उनकी कलाकृतियां हाथो-हाथ बिक जाती हैं. उनकी नई कलाकृतियां खरीदने वालों की कतार लगी रहती है. लंदन के 'द विक्टोरिया एंड अलबर्ट म्यूजियम' ने भी उनके चित्र खरीदे हैं. फिर, भारत महोत्सव के दौरान पेरिस में सेंटर पापेदु के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की समकालीन कला प्रदर्शनी में जिन तीन चित्रकारों की कलाकृतियां शामिल की गई उनमें वे भी एक थीं.

ऐसे कलाकारों की लंबी सूची में बंगलूर की 22 वर्षीया मूर्तिकार पुष्पमाला का नाम

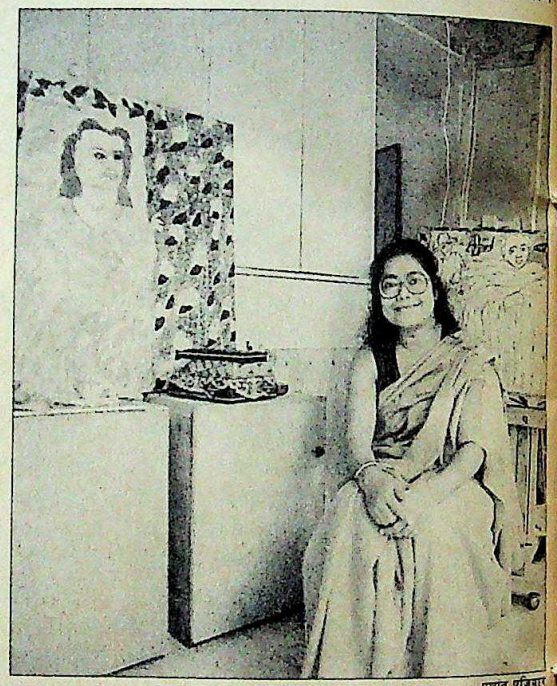

प्रभात पटिवार

अर्पिता सिंह (दाएं); और अपनी कागज की मूर्तियों के साथ जगदीश: नई धुन

प्रभात पटिवार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ी है. करीब दो साल पहले विवान सुंदरम
ारा आयोजित सात मूर्तिकारों की एक समूह
र्शनी में उनकी कुछ नितांत मौलिक
टाकोटा प्रतिमाएं खासी चर्चा का विषय
ही थीं. उन्होंने ये प्रतिमाएं 1985 में
ोदरा में छात्र जीवन के दौरान बनाई थीं.
ुमाला की कलाकृतियां पिछले त्रिनाले में
मिल की गई थीं. कलाकारों और खरीदारों
उन्हें काफी सराहा गया है.
फिर, जगदीश हैं. हैदराबाद से आए यह 32 वर्षीय चित्रकार पिछले चार साल से दिल्ली के गढ़ी कला गांव में काम कर रहे हैं. कागज से बने उनके मौलिक और अवाक् कर देने वाले विशाल मूर्तिशिल्प खूब बिके. ये मुर्तिशिल्प देखने में तो लुगदी से बने लगते हैं पर दरअसल ये दफती से बने पुरुष और महिलाओं के चित्र हैं. वे देश भर में अपने बनाए चित्रों और कागज के मूर्तिशिल्पों को बेचते हैं. वे महसूस करते हैं कि पुरानी पीढ़ी अब 'निस्तेज हो गई है और नए कलाकारों की नकल करती है'.

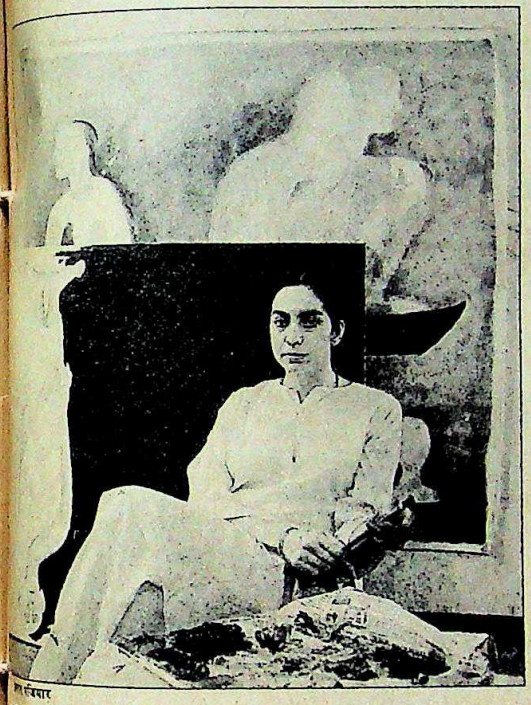

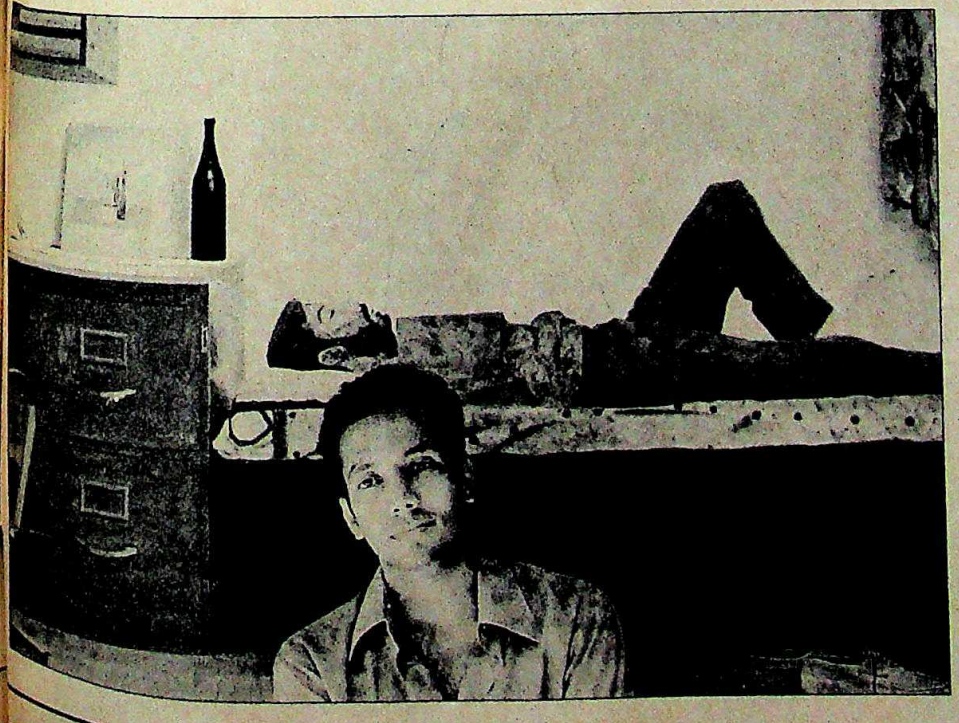

अर्पणा कौर (बाएं); अतुल डोडिया: शहरी आम आदमी का चित्रण

इस नई प्रवृत्ति को इस तथ्य से भी बढ़ावा मिला है कि महानगरों में नई-नई कला दीर्घाएं उसी तरह उग आई हैं जैसे '70 के दशक में फास्ट फूड वाले रेस्तराओं की बाढ़ आ गई थी. बंबई के बांद्रा इलाके में 'डिजाइन-स्केप' नाम से एक नई दीर्घा खुली है. दस्तकारी और रंग-बिरंगे परिधानों के साथ अब बुटीकों में कलाकृतियां भी बिकने लगी हैं. दरअसल एक नई व्यावसायिक दीर्घा 'एरेसा' के कर्ताधर्ताओं ने कलाकारों और डिजाइनरों को एक मंच पर लाकर एक नया परिधान 'आर्ट बियर' बाजार में ला दिया. बंगलूर में सारा अब्राहम के अथक परिश्रम से चलती सीस्ता गैलरी ने भारत भर के बेहतरीन कलाकारों को अपनी ओर खींचा है और कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां भी आयोजित की हैं. दिल्ली में दो और नई दीर्घाएं खुल गई हैं. यहां के पांच सितारा होटलों में कला को बढ़ावा देने का काम शुरू हो गया है. कलकत्ता की चित्रकूट दीर्घा ने तो खरीद-फरोख्त का जैसे बीड़ा ही उठा लिया है, पर सिर्फ बड़े नामों की कलाकृतियों का ही.

और तो और, खुद कलाकारों द्वारा अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी के लिए व्यावसायिक दीर्घाओं को किराये पर लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. मसलन, दिल्ली की त्रिवेणी कला दीर्घा में अगली गर्मियों तक का आरक्षण हो गया है. अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे कला के छात्र और कुछ तो स्कूलों में पढ़ रहे छात्र भी अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाने लगे हैं. उनमें बहुत-सी तो बिकती भी हैं.

अभी ज्यादा अर्सा नहीं हुआ कि कला की दुनिया सामान्य गति से ही चला करती थी. जाहिर है, इनमें सदाबहार दिग्गज मकबूल फिदा हुसैन अपनी सफेद दाढ़ी और ब्रुश के साथ उपस्थित रहते ही थे. और उनके बाद कृष्ण खन्ना, अकबर पदमसी; रज़ा, साबवाला और कई दूसरों का काफिला हुआ करता था. संघर्षरत युवा और अपरिचित कलाकारों का नाम तो दूर पीछे होता था.

लेकिन अब बाजार में तेजी है, दीर्घाओं में पिछले साल कलाकृतियों की कीमत में 25 फीसदी वृद्धि हुई. कला बाजार में एकाएक आई पैसे की बाढ़ का सबसे ज्यादा फायदा उन कम चर्चित कलाकारों को मिल रहा है जिनकी कलाकृतियों की कीमत उछाल लेने लगी है. पिछले महीने बंबई में बड़े पैमाने पर आयोजित 'क्राई' प्रदर्शनी में कुल 180 चित्रों में से 130 की बिक्री एक ही दिन में हो गई. दरअसल, कुछ जाने-माने कलाकारों की औसत दर्जे की कलाकृतियां उतनी नहीं बिकीं जितनी अनजान कलाकारों की. वैसे उन्होंने अपने बेहतरीन चित्रों को ही प्रदर्शनी में भेजा था.

एकाएक यह अंधाधुंध खरीद क्यों होने लगी? एक जवाब तो यही है कि कला बाजार में अब उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने चित्रों के साथ भूपेन खक्कर (इंसेट में) और नवजोत (दाहिनी ओर इंसेट): बढ़ती साख

वर्ग की भी पहुंच हो गई है. चेकोस्लवाकियाई चित्रकांचों, सेजां के सेबों की प्रतिकृतियों और फ्रांसीसी फर्नीचरों के नकलों से ऊबकर नफीस भारतीयों को अब देसी कलाकृतियों की तलाश है. दिल्ली की प्रतिष्ठित और अग्रणी कला दीर्घा 'आर्ट हेरीटेज' के रोशन अल्काजी बताते हैं, "कलाकृतियों की खरीद में अब इन्हीं की मांग है. पहले हमारे खरीदारों में 90 फीसदी विदेशी और 10 फीसदी ही भारतीय हुआ करते थे. अब यह सिलसिला उलट गया है. वेतनभोगी लोग-शिक्षक, बड़े-बड़े व्यवसायी और पत्रकार—अब कलाकृतियों को खरीदने लगे हैं."

वडोदरा के प्रतिष्ठित कलाकार भूपेन खक्कर के अनुसार नई पीढ़ी के कलाकारों के प्रति रुझान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि "उनकी कलाकृतिया सस्ती हैं और खरीदारों को पता है कि पांच साल के भीतर वे पुराने कलाकारों को पीछे छोड़ देंगे." बंबई की सुप्रसिद्ध पंडोल आर्ट गैलरी के ददीबा पंडोल कहते हैं, "पहले लोग गैलरी में टहलते आते और तुरंत बाहर निकल जाते थे. अब वे कुछ देर रुकते हैं और पूछते हैं कि फलां-फलां कृति का कलाकार कौन है. जो बड़े नामों वाली कलाकृतियां नहीं खरीद सकते उनकी रुचि अब ग्रॉफिक्स, वाटरकलर और कुछ कम चर्चित कलाकारों में बढ़ रही है."

लेकिन कला की दुनिया में आए इस बदलाव का असली सूत्र तो कला के प्रति बढ़ रही जागरूकता ही है. पत्रिकाओं और अखबारों के रंगीन परिशिष्टों के साथ-साथ नीलामी के धर्मार्थ आयोजनों से कला की दुनिया के प्रति आकर्षण बढ़ा है.

सिनेमा और टेलीविजन समाज में जो कुछ चल रहा है, उसके अच्छे मापयंत्र हैं. दिल्ली की धूमिमल आर्ट गैलरी के रवि जैन बताते हैं कि आजकल शायद ही कोई टीवी धारावाहिक हो जिसमें दीवारों पर कलाकृतियां न लटक रही हों और "इनमें ज्यादातर नए कलाकारों की ही होती हैं."

मकान बनाने की होड़ भी नई कलाकृतियों की खरीद में एक सहायक तत्व है. धनी बड़े नामों के पीछे भागते है और अपेक्षाकृत कम धनी अनजान कलाकारों की कलाकृतियां खरीदते हैं जो उनकी दीवारों की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सामाजिक हैसियत बढ़ाने में भी सहायक होती हैं. दूसरी तरफ नवविवाहित जोड़े अपने फ्लैट की दीवारों को सजीव बनाने के लिए कलाकृतियों की टोह में दीर्घाओं का चक्कर लगाते हैं.

वास्तुशिल्पी भी अपने ग्राहकों के लिए कलाकृतियों की खोज में अक्सर दीर्घाओं के चक्कर काटते हैं. हाल ही में पंडोल कला-दीर्घा से एक नवधनी उद्योगपति ने आधा दर्जन तैलचित्र खरीदा. यह उद्योगपति दीर्घा में अपने सलाहकारों और वास्तुशिल्पी के साथ आया था. हाल ही में वह बंबई छोड़ सूरत जा बसा था और वहां अपने दफ्तर को एकदम बंबई जैसा रंग देना चाहता था.

अनजाने कलाकरों के प्रति खरीदारों के आकर्षण की एक खास वजह उनकी कलाकृतियों का आधुनिक होना भी है. इनमें से कुछ की कलाकृतियां मौजूदा दौर में भी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं. इस पीढ़ी ने औपनिवेशिक विरासत को अपने कंधे से झटक दिया है. उनमें पूर्ववर्तियों की तरह प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए यूरोप की ओर ताकने की स्थिति भी नहीं रही. उनकी कलाकृतियों में आत्मविश्वास की झलक मिलती है.

नए कलाकार की छवि अब विश्वास से भरे एक व्यक्ति जैसी है, जिसका पहले के कलाकारों में अभाव था. पुष्पमाला बताती हैं, "हमें अब कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है. अब देसी या यूरोपीय होने की कोई जरूरत नहीं है. ये मुद्दे अब अप्रासंगिक हो गए हैं. भारतीय कला, फिल्म, नृत्य, नाटक—यह पूरा रचना संसार एक-दूसरे से गुंथा हुआ है. अब यही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं."

पुष्पमाला और आज के दूसरे कई सफल चित्रकार नए कलाकारों को भारतीय कला के ही वारिस मानते हैं. यूरोपीय शैलियों और गुरूओं को नकारकर वे आजादी के बाद के चार दशकों की कला की समीक्षा करते हैं. डॉक्टर और चित्रकार सुधीर पटवर्धन कहते हैं, "मुझे आरा से ही प्रेरणा मिलती है, जर्मनी में जन्मे और फले-फूले अभिव्यंजनावाद से नहीं."

29 वर्षीया अतुल डोडिया की तरह कई नए कलाकारों को नई खोज माना जाता है. खक्कर की तरह वे सभी 'आम आदमी' को ही अपनी चित्रकारी का विषय बनाते हैं. अपनी कृतियों के बारे में डोडिया कहते हैं, "मेरी रूचि सीधे-सादे लोगों और उनके दैनिक जीवन में है. मैं बंबई के बाहर मध्यमवर्गीय उपनगर घाटकोपर में रहता हूं. पड़ोसी मेरे घर मिलने आते हैं और मेरे चित्रों की सराहना करते हैं. वे चित्रों में वर्णित वस्तुओं और वातावरण को पूरी तरह पहचान सकते हैं."

अभी ज्यादा समय नहीं बीता कि कला बाजार में बी. प्रभा की शैली में ग्रामीण भारत के गंवईपन के चित्र भरे रहते थे. अब नवजोत या अर्पणा कौर की शहरी चिंता को उजागर करने वाले 1984 के दंगों पर बने चित्रों को भी. बाजार में जगह मिलने लगी है.

—मधु जैन, बंबई और दिल्ली में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुरानी आदत बदल डालो

दोहरा लाभ उठालो

पुराने ज़माने के रेज़र ब्लेड से विदा लो.

और अपनालो विल्मन II. सुघड़,सलोना, आधुनिकतम ट्विन-ब्लेड शेविंग सिस्टम. साफ-सुथरी, चिकनी, बेहतर शेव बनाये.

विल्मन II का काम बिल्कुल निराला. परिपूर्ण शेव के लिए कार्ट्रिज में वैज्ञानिक ढंग से नपे-तुले कोण पर दो ब्लेड फिट होते हैं. पहला ब्लेड बाल को खड़ा करके अधिकांश को काट देता है. साथ ही साथ दूसरा ब्लेड बाल को त्वचा तक बिल्कुल साफ कर देता है.

नतीजा अगर एक से कुछ छूटे तो दूसरे से कुछ न छूटे!

यह है दोहरा लाभ!

यही तो रवि शास्त्री इस्तेमाल करते हैं विल्मन II. ट्विन-ब्लेड सिस्टम. विल्किनसन टेक्नॉलॉजी की श्रेष्ठतम रचना.

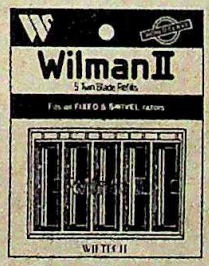

WILTECH
Leaders in quality
Leaders in twin-blades

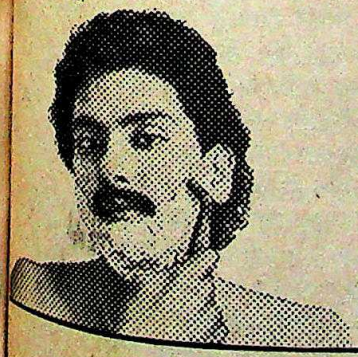

अपनाइये
विल्मन II
वर्ल्ड क्लास ट्विन-ब्लेड

शेव के गुर जानने के लिए मुफ्त पुस्तिका हेतु विल्टेक इंडिया लिमिटेड, एम जी रोड, बेंगलोर-560 001 को लिखें.

आपकी चहेती पत्रिका आपके दरवाज़े पर न खरीदने का झंझट... न खत्म होने का डर

इस सुविधा का लाभ उठाइए.
आपनी चहेती इंडिया टुडे
घर बैठे – नियमित पाइए.
न खरीदने जाने की ज़रूरत...
न अंक खत्म होने का डर,
इंडिया टुडे
समय से पहुंच जाए आपके घर !
बस कूपन भर कर भेज दीजिए,
देर मत कीजिए !

नाम : _____

डाक पता : _____

मूल्य वार्षिक रु 120/-
भुगतान का माध्यम – चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट
कृपया चैक निम्नलिखित नाम पर बनाएं और इस पते पर भेजें :
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. नं. 69, दिल्ली मथुरा रोड,
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

MILESTONES/IT/120

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

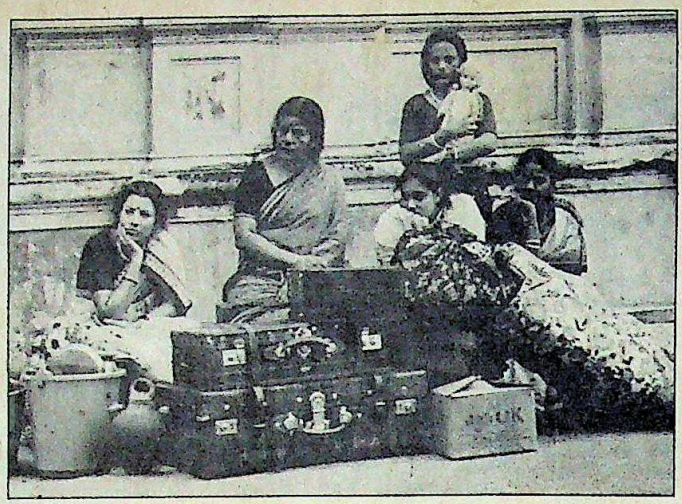

रुक्मिणी

औरत तेरे रूप अनेक

कमला दास की कहानी पर पहली फिल्म

भारतीय औरत की तस्वीर रुबिक-क्यूब की तरह असंख्य चेहरों वाली है. साहित्य के पन्नों में, सिनेमा के परदे पर और अखबार के कॉलमों में ये चेहरे हर रोज बदलती इबारतों के साथ सामने आते रहते हैं—कभी डीटीसी के लफंगे कर्मचारियों से इज्जत बचाने को जूझती मनीषा वर्मा के रूप में तो कभी इस हाथ से उस हाथ बिकती कमला के रूप में; कभी खुराफाती ड्राइवरों की नाक में दम करने वाली 'क्रेन बेदी' के रूप में तो कभी बदले की आग में दहकती 'जख्मी औरत' के रूप में.

मलयाली फिल्म निर्देशक 45 वर्षीय पी.के. कुमारन ने अपनी नई फिल्म 'रुक्मिणी' में हिंदुस्तानी औरत की जो तस्वीर पेश की है वह भी इन्हीं असंख्य चेहरों में से एक है—कोठों की बदबूदार कोठरियों में सांस-दर-सांस घुलती, बिखरती 12 वर्षीया रुक्मिणी की, जिसे धंधे में पूरी तरह उतरने से पहले ही इस धंधे का खौफनाक रूप सालने लगा है. फिल्म की पटकथा विख्यात लेखिका कमला दास की मूल अंग्रेजी कहानी 'केज' (पिंजरा) पर आधारित है जो उन्होंने 60 वाले दशक में लिखी थी. यह पहला अवसर है जब कमला दास की किसी कृति को फिल्माया गया है. और पहली बार वे किसी फिल्म के निर्माण में व्यक्तिगत तौर पर गहराई से जुड़ीं.

एक ऐसे व्यावसायिक माहौल में जहां फिल्मों के बजट लाखों और करोड़ों के आंकड़ों को छूते हों वहां कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम में मात्र 20 दिन की शूटिंग और 25 से भी कम रोल फिल्म खर्च करके फिल्म पूरी कर लेना फिल्म जगत के लिए एक अजूबे की बात होगी. लेकिन कुमारन ने यह कर दिखाया है. कला फिल्मों को छोड़कर व्यावसायिक सिनेमा की शरण में जाना और अब इस अंदाज में उनका फिर से कला फिल्मों में लौटना यकीनन दर्शकों के लिए भी एक नया अनुभव होगा.

दो घंटे लंबी यह फिल्म मुख्य रूप से एक ही चरित्र रुक्मिणी के आसपास घूमती है. लेकिन एक व्यक्ति पर केंद्रित रहते हुए भी वह दर्शक को कोठों और उनमें रहने वाली वेश्याओं की जिंदगी के एकदम अंतरंग कोनों से भी रू-ब-रू कराती है. फिल्म की नायिका रुक्मिणी (अंजु) को उसका सौतेला पिता अपनी हवस का शिकार बनाता है. इस पर उसकी मां देवकी उसे घर से दूर भेजने का फैसला करती है और आखिरकार उसे सत्या बाई (मावेलिक्करा पोन्नम्मा) के कोठे पर छोड़ आती है. यह वही कोठा है जहां से कुछ साल पहले देवकी का पति उसे अपने साथ ले गया था.

कोठे की ज़िंदगी की बारीकियों से बेखबर रुक्मिणी वहां अपने से दो साल बड़ी सीता से दोस्ती करती है जो बीमार और मरियल है. कोठे के चरित्रों में एक है मीरा (लिज़ी) जो सबसे पुरानी वेश्या है और एक विद्यार्थी से इश्क करती है जो उसे इतिहास पढ़ाता है. अपने प्रेमी से ठुकराई हुई राधा है जो अभी भी उसे प्रेमपत्र लिखती है. दो बच्चों की मां सरस्वती है जिसका बीमार पति हर महीने आकर उससे अपना खर्च ले जाता है. संगीतकार देवराज के संगीत की लहरों पर कोठे की रोजमर्रा की जिंदगी अपने ढर्रे पर चलती रहती है. पर एक दिन छोटी लड़कियों का शौकीन और वहां का एक नियमित ग्राहक एक अधेड़ इंस्पेक्टर (नेदुमुदी वेणु) वहां आता है और रुक्मिणी पर मोहित हो जाता है. वह उसे चॉकलेट और नए कपड़ों का लालच देता है पर रुक्मिणी चाहती है कि वह उसे उसके असली पिता से मिला दे जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानती.

कोठे से बेदखल होने के बाद सड़क पर: अनिश्चय

इसी दौरान कोठे पर ही गर्भपात कराने के चक्कर में सीता की मौत हो जाती है. रुक्मिणी के लिए यह सदमा सह पाना मुश्किल हो जाता है और वह इंस्पेक्टर से उसे वहां से दूर ले जाने की मिन्नत करती है. इंस्पेक्टर का मन पसीज जाता है. लेकिन इससे पहले कि फिल्म मूल कहानी की तरह यहीं खत्म हो जाए, कहानी एक नाटकीय मोड़ ले लेती है. सत्या बाई का बेटा जो उसे दस साल पहले छोड़कर कहीं भाग गया था, चिट्ठी भेजकर बताता है कि वह मां के पास लौट रहा है. लेकिन कोठे की यह खुशी अचानक ही दुख में बदल जाती है. मकान मालिक वेश्याओं को कोठे से बेदखल कर देता है और वे सड़क पर आ जाती हैं. सड़क पर चलने वाली दुनिया उनसे बेखबर अपनी गति से कदम-दर-कदम आगे बढ़ती चली जाती है.

कहानी के इस नए अंत के बारे में कुमारन कहते हैं, "क्योंकि मैं जिंदगी की असलियत दिखाने में विश्वास रखता हूं इसलिए 'रुक्मिणी' भी मेरा ऐसा ही बयान है." यह कहानी इस मायने में भी अनूठी है कि कमला दास की कहानियां आम तौर पर उच्च मध्यम वर्ग के पुरुष और नारी पात्रों पर केंद्रित रहती हैं. इस कहानी के बारे में वे कहती हैं, "मेरा मुख्य लक्ष्य बच्चों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना है." अब वे अपनी एक अन्य कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन खुद करने जा रही हैं.

आज से 16 साल पहले एशिया-72 के दौरान कुमारन को अपनी 100 सेकेंड लंबी फिल्म 'रॉक' के लिए स्वर्ण पदक मिला था. बाद में उनकी 'स्वयंवरम' भी पुरस्कृत हुई और 'अतिथि' को भी तारीफ तो काफी मिली पर बॉक्स ऑफिस पर वह कामयाब नहीं हो पाई. इस बीच उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों की ओर रुख किया लेकिन चार-पांच फिल्में बनाने के बाद ऊबकर वे फिर से कला फिल्मों की ओर आकर्षित हुए हैं. 'रुक्मिणी' के बारे में उन्हें उम्मीद है कमला दास और उनके लिए यह फिल्म शुभ साबित होगी.

—ललिता शिलीम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंजीनियरिंग कॉलेज

अध्यापकों का भारी अकाल

खाली पदों की संख्या एक दशक में 50 फीसदी बढ़ी

तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है. और जो हालात हैं 21वीं सदी के उन्नत और परिष्कृत तकनीक वाले औद्योगिक युग में प्रवेश करने तक यह संख्या तेजी से बढ़ती ही जाएगी.

लेकिन वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है. इंजीनियरिंग कॉलेजों में धीरे-धीरे एक संकट घिरता जा रहा है. इनके लिए शिक्षकों का भारी अकाल पड़ता जा रहा है. हालांकि देश भर के इन उच्च शिक्षा वाले तकरीबन 300 कॉलेजों में काम सामान्य ढंग से चलता लग रहा है, लेकिन इन कॉलेजों के प्रोफेसर, प्राचार्य और यहां तक कि शिक्षा अधिकारी भी शिक्षकों की तेजी से बढ़ती कमी से चिंतित नजर आते हैं. अपने विभागों के लिए उन्हें योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे. इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या पिछले एक दशक में 50 से 60 फीसदी तक बढ़ गई है.

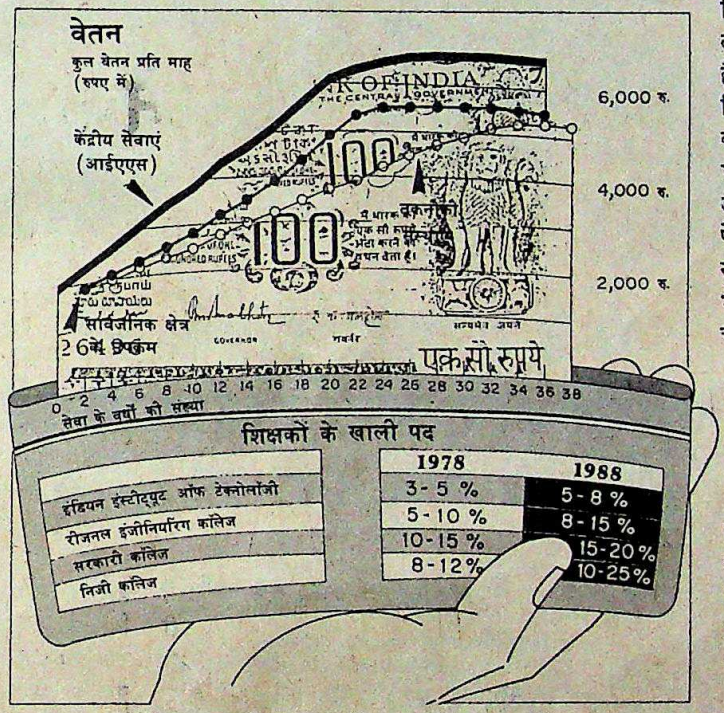

सरकारी अनुमानों के अनुसार 10 फीसदी की औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस सदी के अंत तक 60,000 तकनीकी शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे शिक्षकों की वर्तमान संख्या इसकी एक तिहाई भी नहीं है. इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान, रोबोट विज्ञान और सूचना विज्ञान जैसे विकासशील क्षेत्र इस कमी से ज्यादा ग्रस्त हैं.

पिछले कुछ वर्षों में हुई औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ प्रतिभा पलायन भी बढ़ता रहा और देश के मेधावी स्नातक इंजीनियर अध्यापन और अनुसंधान की ओर से मुंह मोड़ने लगे. आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान भी इस अभाव से परेशान दिखते हैं. दिल्ली आईआईटी के उपनिदेशक (फैक्ल्टी) आर.सी. मल्होत्रा कहते हैं, "खारिज हो चुके लोग यहां अध्यापन के लिए आते हैं." बंबई आईआईटी के एक अध्ययन के अनुसार संस्थान के 25 से 35 फीसदी स्नातक विदेश चले जाते हैं. बाकी के एक चौथाई मार्केटिंग या मैनेजमेंट क्षेत्रों में चले जाते हैं. 1986 में गठित आईआईटी समीक्षा समिति के मुताबिक, "यदि प्रतिभाशाली सक्षम युवकों को इस तरफ मोड़ने की कोशिशें नहीं की गईं तो खतरा यह है कि इन संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी."

लेकिन आईआईटी की बनिस्बत आम इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह संकट ज्यादा गहरा है. कर्नाटक के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज तो अस्थाई अध्यापकों के बूते पर ही चल रहे हैं. ये लोग ज्यादातर नौकरीपेशा इंजीनियर हैं जो अपने फालतू समय में पढ़ाने चले आते हैं. इनके पास डिग्री के अलावा आम तौर पर कोई और योग्यता भी नहीं होती. कुछ साल पहले नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि अध्यापकों के 50 फीसदी पद खाली थे. हारकर सरकार को योग्यताओं में थोड़ी छूट देनी पड़ी. नतीजतन दोयम दर्जे की प्रतिभा वाले लोग अध्यापन के लिए आने लगे.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास अध्यापन के स्तर को लेकर छात्रों के शिकायती पत्र लगातार आते रहते हैं. इंजीनियरिंग अध्यापकों के लिए नए वेतनमानों और सुविधाओं के प्रस्तावों पर डेढ़ साल की हील-हुज्जत और उलटफेर के बाद अंततः पिछले महीने एक नया प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल में भेजा गया. इस प्रस्ताव में अध्यापकों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रावधान तो है, लेकिन अध्यापकों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए उनकी संख्या में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है. दिल्ली आईआईटी के पूर्व निदेशक आर.एन. डोगरा की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल 1987 में जो रिपोर्ट पेश की उसमें दिए गए अहम सुझावों में एक यह सुझाव भी था. सरकारी सहायता से चलने वाली भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के कार्यकारी सचिव पी.जे. जॉर्ज कहते हैं, "जब तक इंजीनियरिंग के अध्यापकों को निजी और सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वाले इंजीनियरों जितना वेतन और सुविधाएं नहीं दी जातीं, तब तक हालात बदलेंगे नहीं."

इंजीनियरिंग के अध्यापकों के स्तर और काम के माहौल में सुधार बहुत जरूरी है. यह सुझाव सरकार ने मान भी लिया है. नए सुझावों के तहत प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों में सहयोग का प्रावधान है. कोई प्रोफेसर यदि अपने सहयोगियों या छात्रों के साथ किसी कंपनी की परियोजना हाथ में लेते हैं तो वे तकनीकी फीस ले सकते हैं. शोध छात्र, जिन्हें अब 1800 रु. की मासिक छात्रवृत्ति मिलती है, स्नातक से नीचे की कक्षाओं को पढ़ाया करेंगे.

कुछ इंजीनियरिंग अध्यापक तो इन नए प्रस्तावों को लेकर काफी उत्साहित हैं, पर कुछ सरकार के ढीले रवैये और मामले को गंभीरता से न लेने की प्रवृत्ति पर नाराज हैं. डोगरा गुस्से में कहते हैं, "हम शानदार कामकाज की बात तो करते हैं, लेकिन काम इसके ठीक विपरीत."

—डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

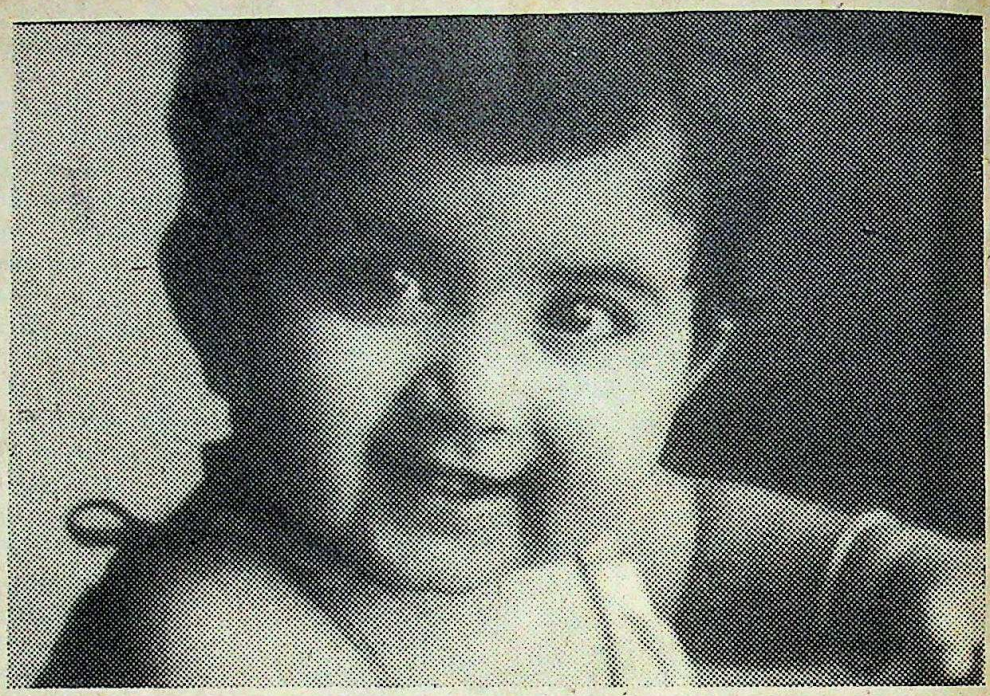

ये है यूनाइटेड इंडिया की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेने की एक नन्ही-सी वजह.

आपका नन्हा-मुन्ना. आपका अपना परिवार.

उनके सुनहरे भविष्य की ज़िम्मेदारी आप पर है और उनकी खुशियों में ही तो आपकी खुशी है.

इसीलिए तो आप हर संभव कोशिश करते हैं कि उनकी खुशियां और खुशहाली हमेशा बनी रहें.

यूनाइटेड इंडिया की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के सहारे आप निश्चिंत रहेंगे क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश आपके जीवन में अचानक संकट आ भी जाए, तो भी आपके परिवार का भविष्य अपंग नहीं होगा.

इस पॉलिसी के अंतर्गत, स्थायी या अस्थायी रूप से अंपग हो जाने पर, स्थायी रूप से आंशिक अपंगता की स्थिति आ जाने पर या दुर्घटना द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचने से मृत्यु हो जाने पर, मुआवज़ा दिये जाने का प्रावधान है, दुर्घटना के उपरांत डॉक्टरी इलाज पर हुए खर्च की मर्यादित भरपाई के प्रावधान की सुविधा भी इस पॉलिसी को बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है.

रियायती प्रीमियम-दरों पर, पूरे परिवार के लिये एक पेकैज-पॉलिसी तथा 'ऑन ड्यूटी'/'ऑफ ड्यूटी' बीमा-पॉलिसियां भी रियायती, प्रीमियम-दरों पर उपलब्ध हैं.

इसलिए आप कंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हों, पशु-डॉक्टर हो, बैंक में कैशियर हों, मशीन ऑपरेटर हों या दूकानदार... यूनाइटेड इंडिया की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेना एक समझदारी का काम होगा. जिससे यह साफ जाहिर हो जायेगा कि आप अपने परिवार का कितना ख्याल रखते हैं.

जल्दी करें. हमारे १००० से भी अधिक केंद्रों में से किसी में भी संपर्क करें.

स्वतंत्रता के चालीस वर्ष
FORTY YEARS OF FREEDOM

UNITED INDIA

युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेन्स कं. लि.

(जनरल इन्श्यूरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक संस्था)

२४, व्हाइट्स रोड, मद्रास-६०००१४.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

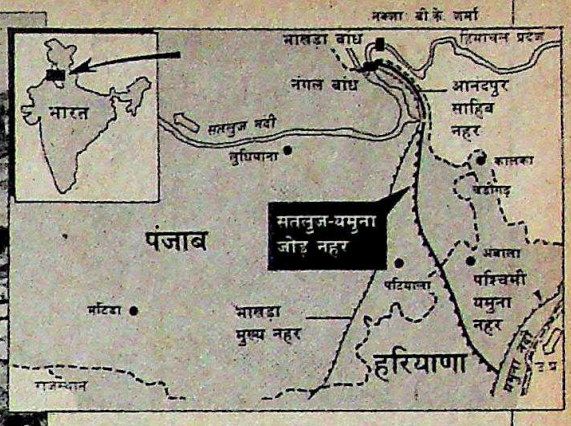

पंजाब में निर्माण कार्य का जायजा लेते देवीलाल: अंतहीन प्रतीक्षा

जोड़ नहर

अटकती-भटकती धारा

अड़चनों, विवादों और बिसरे वायदों के कारण निर्माण में देरी

करीब दस साल पहले जब सतलुज-यमुना जोड़ नहर परियोजना शुरू करने के बारे में सोचा गया था तो बंजर जमीन पर फसल उगाने को प्रयासरत हजारों हरियाणवी किसानों को अपने सपने साकार होते दिखे. कंक्रीट से बनी 213 किलोमीटर लंबी इस नहर के जरिये हरियाणा को रावी और व्यास नदियों के पानी का अपना हिस्सा मिलना तय हुआ. उम्मीद थी कि इससे तीन लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और सालाना 10 लाख टन अनाज पैदा करने में मदद मिलेगी. लेकिन राजनीति के दलदल में फंसी इस परियोजना ने एक ही दिशा में तरक्की की दिखती है. और वह यह कि नहर का काम पूरा होने की मियाद बढ़ती ही गई है.

यह बात दीगर है कि पंजाब सरकार इसके अंतिम चरण पर पहुंचने के बड़े-बड़े दावे करती आ रही है. इस बीच, नहर की लागत भी आसमान छूने लगी है. अभी तक इसमें 350 करोड़ रु. से अधिक की रकम खर्च हो चुकी है, हालांकि शुरुआती अनुमान 66.45 करोड़ का ही था. पिछले आठ साल में कम-से-कम 10 बार बदले गए सरकारी अनुमानों के अनुसार इसके पूरा होने पर अभी 100 करोड़ रु. और खर्च आएगा.

ये अनुमान भी कम करके बताए गए हैं. इनमें वह नुकसान शामिल नहीं जो इस साल आई बाढ़ से नहर के पहले बने हिस्सों को हुआ है. पर इस नहर परियोजना पर काम कर रहे विभिन्न सरकारी संगठनों के बेईमान ठेकेदारों और इंजीनियरों ने बाढ़ की आड़ में तत्काल संशोधित लागत अनुमान पेश कर दिए. इस साल मई में आतंकवादियों द्वारा 30 बिहारी मजदूरों की हत्या को भी पिछले छह महीने में परियोजना की सुस्त रफ्तार और नतीजतन बढ़ी लागत का कारण बताया गया. लेकिन अब तो बिहारी मजदूर भी लौट आए हैं, फिर भी काम में तेजी आने के कोई आसार नहीं दिखते. बहरहाल, सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ करके ठेकेदार लोग संशोधित अनुमानों को मंजूर कराने में पीछे नहीं रहेंगे.

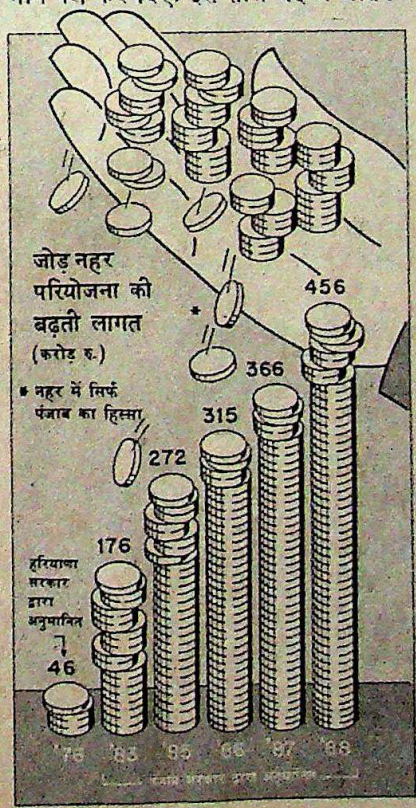

चार्ट: बी.के. शर्मा

1976 में जब हरियाणा सरकार ने नहर परियोजना के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट केंद्र को भेजी, तब से बढ़ती लागत इस परियोजना की विशेषता रही है. मूल योजना के अनुसार हरियाणा को नहर के 91.16 किमी और पंजाब को 122 किमी हिस्से का निर्माण करवाना था. लेकिन काम कभी सिरे नहीं चढ़ पाया क्योंकि पंजाब पानी देने का इच्छुक नहीं था.

इसलिए परियोजना की मूल समय सीमा यानी 1980 तक, पंजाब सरकार ने भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं किया था जबकि हरियाणा ने अनुमान से भी सात करोड़ रु. ज्यादा खर्च करके अथवा 28.30 करोड़ रु. की लागत से नहर के अपने हिस्से का काम लगभग निबटा दिया. पंजाब की टालमटोल इसलिए भी आश्चर्यजनक थी क्योंकि उस दौरान वहां भी हरियाणा की तरह इंका की ही सरकार थी. केंद्र के दबाव के बावजूद पंजाब अड़ा रहा. आखिरकार, दरबारा सिंह की अगुआई वाली पंजाब सरकार हरियाणा को अनुग्रहित करने को राजी हो गई. दिसंबर 1981 में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौजूदगी में एक समझौते पर दस्तखत किए. परियोजना पूरा करने की नई समय सीमा दिसंबर 1983 रखी गई और उस पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

192 करोड़ रु. की लागत आंकी गई.

पर पंजाब द्वारा हरियाणा पर निष्क्रियता का आरोप लगाने से यह समय सीमा कागज पर ही रही. हरियाणा पर आरोप था कि उसने पंजाब में नहर निर्माण पर हुई लागत का एक हिस्सा देने की अपनी जिम्मेदारी के बावजूद 1982 से 1984 तक कोई पैसा अदा नहीं किया. परियोजना पर काम कुल मिलाकर बीसियों ऐसी बैठकों तक ही सीमित रहा जिनमें योजनाएं बनतीं और समीक्षाएं की जातीं. सैकड़ों अधिसूचनाओं और स्मरणपत्रों का आदान-प्रदान हुआ लेकिन जमीन पर काम वास्तव में ठप ही रहा. 1984 के शुरू में हुई एक समीक्षा बैठक में नहर के मुख्य अभियंता ने दावा किया कि बहुत-सी जगहों पर भूमि अधिग्रहण का काम इसलिए पूरा नहीं हो सका क्योंकि हरियाणा ने पंजाब सरकार को भुगतान करने में टालमटोल की. समय सीमा फिर 1986 तक बढ़ा दी गई.

इस बीच, केंद्र अपनी राजनैतिक चालें गढ़ता रहा. हरियाणा में नहर के चुनावी महत्व के मद्देनजर उसने जोड़ नहर के समझौते का मुद्दा खूब उछाला. केंद्र ने वायदा किया कि नहर पूरा करने के काम में अब कोई बाधाएं नहीं आएंगी. उसने इस मामले में पंजाब के काम पर निगरानी रखने का भी फैसला किया ताकि 15 अगस्त 1986 तक नहर का निर्माण पूरा हो जाए.

लेकिन वायदे और उम्मीदें एक बार फिर धूल में मिल गईं. पंजाब समझौता लागू नहीं हो पाया. नहर परियोजना भी उसका एक ऐसा हिस्सा थी जो कभी साकार नहीं हो सकी. इसलिए चौथी समय सीमा भी गुजर गई. इससे लागत अनुमान भी बढ़कर 366 करोड़ रु. पर जा पहुंचा.

परियोजना में दिलचस्पी का अगला उभार दिसंबर 1986 में आया. हरियाणा विधानसभा चुनावों में अभी कुछ ही महीने बाकी थे. तभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने घोषणा की कि केंद्र सतलुज-यमुना जोड़ नहर का सारा खर्च खुद उठाएगा. केंद्र ने वायदा निभाया भी. पैसा आते ही हरियाणा सरकार ने पंजाब से 1987 के अंत तक काम खत्म करने का अनुरोध किया. हमेशा की तरह पंजाब सरकार ने फिर हामी भर दी. पंजाब द्वारा केंद्र से 349.94 करोड़ रु. की रकम ले लेने के बावजूद समय सीमा एक साल तक के लिए फिर बढ़ा दी गई. पंजाब के कृषि विभाग के सचिव रजिंदर सिंह के अनुसार तीन प्रमुख मोर्चों पर स्थिति ठीकठाक रही हैं. वे कहते हैं, "हमने भूमि अधिग्रहण का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है. जमीन की खुदाई का 95 फीसदी और रेखांकन का 88 फीसदी से अधिक काम हो चुका है." उनके मुताबिक बाकी काम एक महीने में निबटा लिया जाएगा.

मगर यह सब आंकड़ेबाजी का ही खेल लगता है. प्रतिशत वाले आंकड़े नहर की सीधी दूरी के मामलों में हैं. पुल और नाले बांधने का काम अभी शुरुआती दौर में ही है. मसलन, नहर अधिकारियों ने कुल 76 पुलों में से 31 का ही पूरा निर्माण किया है. 12 दूसरे पुलों का काम अभी आधा ही हुआ है जबकि बाकियों में यह अभी शुरू

जोड़ नहर के एक हिस्से में चलता काम: सुस्त रफ्तार

भर हुआ है. इसी तरह, पिछले आठ साल में 11 प्रमुख नालों में से दो को बांधने का काम ही पूरा हो पाया है. यही हालत 41 मझोले और छोटे नालों की है. इनमें 17 ही अभी बांधे जा सके हैं. मोटे अनुमानों के अनुसार भी इस देरी से कम-से-कम 50 करोड़ रु. की लागत बढ़ जाएगी.

पर दूसरे मामलों में इससे भी बड़ी अड़चनें हैं. मसलन, सिरसा प्रशाखा को ही लें. नहर की यह शाखा बनाने के लिए लगातार छह महीने काम चलाना जरूरी है पर वह तो अभी शुरू भी नहीं हो पाया. वजह यह है कि सरकार और ठेकेदार में कानूनी लड़ाई ठन गई थी. पिछले महीने इसका स्थगन आदेश तो रद्द हो गया पर अभी दूसरा ठेकेदार मुकर्रर नहीं किया गया है. दूसरी प्रमुख अड़चन एक अंतरसंपर्क जलमार्ग बनाने के मामले में 1980 से पंजाब और हरियाणा के बीच चला आ रहा विवाद है. पंजाब एक पनबिजली संयंत्र लगाने के लिए यह जलमार्ग बनाना चाहता है. यह नंगल जलमार्ग को सतलुज-यमुना जोड़ नहर से जोड़ेगा. हरियाणा चाहता है कि इस परियोजना से पैदा हुई बिजली अंतरराज्यीय प्रस्ताव के तहत उसे भी दी जाए पर पंजाब मना कर रहा है.

एक गुत्थी और है. हरियाणा यह मांग भी कर रहा है कि जलमार्ग पर पंजाब सरकार का नियंत्रण न हो. रंजिंदर सिंह कहते हैं, "बदकिस्मती से हरियाणा सरकार 36 मेगावाट के छोटे बिजली संयंत्र पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होने देना चाहती." उधर, हरियाणा के कृषि और बिजलीमंत्री वीरेंद्र सिंह इसका नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को सौंपना चाहते हैं जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है.

इन सारे विवादों के बीच सतलुज-यमुना जोड़ नहर दिसंबर '88 की नई समय सीमा के भीतर भी अब पूरी होती नहीं दिखती. पंजाब सरकार ने खुद हरियाणा को सूचित किया है कि उसके जिम्मे नहर का काम मार्च '89 से पहले पूरा होना मुमकिन नहीं. दोनों राज्यों के अधिकारी भी इसे महज आशावादिता मानते हैं.

अब लगता यही है कि राजनैतिक संयोग जुड़ गए तो यह परियोजना जल्द पूरी हो सकती है. आम चुनाव नजदीक होने से प्रेक्षकों को भरोसा है कि इस परियोजना का काम मध्य 1989 तक पूरा हो जाएगा. इससे इंका को हरियाणा के मतदाताओं के सामने अपनी नेकनीयती साबित करने में मदद मिलेगी. लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है कि इस राजनैतिक जोड़-घटाव के कारण हरियाणा के किसानों की तमाम उम्मीदें मुरझा गई हैं.

—विपुल मुद्गल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आत्मकथा

एक आधी-अधूरी कहानी

'रस' के आचार्य का रसहीन, अनकहा आत्मचरित

अर्धकथा
आत्मकथा
डॉ. नगेंद्र
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली-110002
कीमत: 65 रु.; कुल पृष्ठ: 171

प्रसाद जन्मशती के उपलक्ष्य में अभी-अभी (सितंबर 1988 में) आयोजित साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने विनोदपूर्वक कहा कि 'कामायनी' की जो-जो व्याख्याएं संगोष्ठी में हुई हैं उनको सुनकर वहां मौजूद डॉ. नगेंद्र अनुभव कर रहे होंगे कि 'कामायनी' जो इतने वर्षों से उनके हाथ में थी, अब उनके हाथों से निकल गई. इस टिप्पणी ने गोष्ठी के गंभीर वातावरण को थोड़ा सरस तो बनाया पर नए सोच और पारंपरिक सोच के बीच जो टकराहट भीतर ही भीतर चल रही थी उसे भी उभारकर सामने रख दिया. कुछ अजब नहीं कि उस क्षण डॉ. नगेंद्र के मन में वर्षों पहले का एक प्रसंग कौंध गया हो, जिसका उल्लेख उन्होंने हाल में ही प्रकाशित अपने आत्मचरित 'अर्धकथा' में किया है.

काशी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्राध्यापक दिवंगत पं. केशव प्रसाद मिश्र का परिचय डॉ. नगेंद्र इन शब्दों में देते हैं, "सांस्कृतिक तथा दार्शनिक संदर्भों का प्रामाणिक विवेचन और मार्मिक प्रसंगों का रससिक्त शब्दावली में विश्लेषण करते हुए कामायनी का अध्यापन वे 'अत्यंत तन्मय भाव से किया करते थे." ऐसे यशस्वी अध्यापक और प्रकांड विद्वान का ध्यान डॉ. नगेंद्र ने कामायनी की संरचना में अंतर्व्याप्त दो-एक मनोवैज्ञानिक सूत्रों की ओर यों आकृष्ट किया:

"वासना सर्ग तक मनु श्रद्धा के प्रति केवल पुल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और यह अकारण या संयोग मात्र नहीं है... मनु के पूर्व जीवन के संस्कार प्रलय में सर्वथा विलुप्त हो चुके थे और नव सृष्टि के विकास के साथ-साथ अब वे क्रमशः उद्बुद्ध होते जा रहे थे. उनमें यौन भावना भी थी जो बाह्य उद्दीपन और श्रद्धा के संसर्ग से विकसित हो रही थी. किंतु अभी तक नर-नारी की युग्म-चेतना उनके मन में स्पष्ट नहीं हुई थी. इसीलिए मनु श्रद्धा को अपना सहचर, अतिथि आदि मानकर, उसे उसी रूप में संबोधित करते आ रहे थे. नर-नारी का यह युग्म-भेद उनके मन में 'वासना' सर्ग में जाकर पूर्णतः स्पष्ट होता है. यहां उन्हें पहली बार श्रद्धा के नारी रूप की प्रतीति होती है: 'आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान/ विश्वरानी! सुंदरी, नारी जगत की मान.' आदि पुरुष और आदि नारी के मन के भीतर जो द्वंद्व चल रहा था उसका अंत यहीं आकर होता है. इसके बाद मनु कहीं भी श्रद्धा के लिए पुल्लिग शब्द का प्रयोग नहीं करते. "मिश्रजी मेरी बात बड़े ध्यान से से सुन रहे थे और अंत में कहने लगे, 'हमने अभी तक इस दृष्टि से विचार नहीं किया था. किंतु यह व्याख्या निश्चय ही रोचक है. इससे कामायनी के अर्थ-गौरव में एक नए आयाम का उद्घाटन होता है."

"अंतरंग जीवन नितांत मेरा अपना है—आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है...स्मृतियों को अब भी मैं सहज ही क्रमबद्ध कर सकता हूं. किंतु उसकी कोई सार्थकता नहीं है"

इसी किताब से

यह प्रसंग इसका प्रमाण है कि समय के साथ-साथ व्याख्याएं किस तरह बदलती चलती हैं और नए आयाम उद्घाटित होते हैं. किंतु वही आचार्य नगेंद्र जो एक समय ऐसे उद्घाटन में समर्थ हुए थे, आज जब मनोविश्लेषण शास्त्र के अपने ज्ञान का उपयोग बारंबार अपने अंतर्मन के विश्लेषण के लिए करते हैं तो उनके "कुछ भी हाथ नहीं लगता." उनकी 'अर्धकथा' समर्पित है "अमित स्नेह के दानी उन पात्रों के नाम जो इस अधूरी कहानी में अनाम ही रह गए हैं." पुस्तक के 'मुखबंध' में वे लिखते हैं, "यह मेरे जीवन का अर्द्धसत्य मात्र है—पूर्णसत्य नहीं, क्योंकि पूर्णसत्य को अनावृत करने का नैतिक या अनैतिक साहस मुझमें नहीं है." मगर 'समाहार' में वे अपने अंतरंग जीवन के दो पाथेयों के विषय में बताते हैं, "नारी का स्नेह-संभार जहां मेरी साहित्य साधना को रसमय बनाता रहा है, वहां सहित्य साधना इस स्नेह-संभार के सुख को आंतरिक दीप्ति प्रदान करती रही है. यह अंतरंग जीवन कितना परवश रहा है, इसका अनुभव केवल मैं ही कर सकता हूं. अहंकार से विजड़ित कठोर मुद्रा के भीतर मेरा मन दूसरों के स्नेह पर इतना अधिक निर्भर रहा है कि मेरे बुद्धि-विवेक के लिए वह प्रायः दया का पात्र बन गया है. जब से मैंने होश संभाला है तभी से मैं इस विचित्र अनुभूति से आक्रांत रहा हूं. किंतु इसका कारण अब तक मेरी समझ में नहीं आया."

यह आत्मचरित यदि कालप्रवाह में बहते हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म, पारिवारिक परिवेश, छात्र जीवन, शैक्षिक जीवन और लेखन का नीरस इतिवृत होकर रह गया है, तो इसके कारण की खोज भी हम इस लेखकीय आग्रह में ही कर सकते हैं कि उसे मात्र 'अर्धकथा' बतानी है. लेखक रचनात्मक साहित्य और सर्जनात्मक साहित्य के अंतर को जानता है, "रचना अथवा निर्माण एक योजनाबद्ध, बुद्धिसम्मत प्रक्रिया है जिसके पीछे बहिर्मुखी वृत्ति की प्रेरणा रहती है. सृजन आत्म साक्षात्कार के क्षणों की अनिवार्य प्रक्रिया है जिसमें वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है."

पर यदि उसने 'मुखबंध' का अर्थ 'मुंहबंद' मान रखा हो तब तो यह नतीजा निकलना ही था कि 'समाहार' तक पहुंचने पर भी पाठक 'निराहार' रह जाएं और आत्मकथा या आत्मचरित की जगह केवल आत्मवृत या आत्मतथ्य ही पाएं. ऐसा लगता है कि लेखकीय आत्मनिषेध के कारण ही यह 'अर्धकथा' वैयक्तिक, सामाजिक-राजनैतिक संदर्भों की उपेक्षा करने वाली एक अधूरी कथा बन गई है. आशा करनी चाहिए कि अपने जीवन और समय में रम कर हमारे आदरणीय डॉ. नगेंद्र 'शेषकथा' का भी 'निर्माण' नहीं, 'सृजन' करेंगे. 'रस' के आचार्य में रसात्मकता की क्षमता निस्संदेह है जो यहां भी बीच-बीच में थोड़ी झलकी है.

—अजित कुमार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपन्यास

घायल समाज की बेचारगी

मोहरों की पराजय व नगण्यता देखने की सशक्त कोशिश

मय्यादास की माड़ी
उपन्यास
भीष्म साहनी
राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली
कुल पृष्ठ-273, कीमत: 75.00 रु.

बूढ़े-पुराने साफे, छीजे अंगरखे, बदरंग होते कालीन, घिसी-पिटीं पोशाकें, दीवारों पर लटकती तलवारें, पुरानी पीढ़ी के धुंधले पड़ते चित्र, माड़ी की खस्ता बेरंग मेहराबें, हवेली की नीलामी, मिरगी के मरीज, रखैलों के बेटे— पिटे हुए मोहरों का जुलूस है यह जिसे मय्यादास की माड़ी में उपन्यासकार भीष्म साहनी ने अनोखी एकाग्रता से प्रस्तुत किया है. एक घायल समाज की बेचारगी, पराजय और नगण्यता देखने की सशक्त कोशिश. उपन्यास की आधारभूमि हारी हुई व्यवस्था के भयावह यथार्थ में औंधे मुंह बिछी पड़ी है. समय है पंजाब का एकछत्र राज्य हार जाने का और रफ्ता-रफ्ता लाल होकर अंग्रेजी राज्य की जड़ों के गहराई तक धंसते चले जाने का.

किसी भी अच्छे उपन्यास के लिए जो कलात्मक समग्रता उसके शिल्प के खरेपन की कसौटी हुआ करती है वह मय्यादास की माड़ी के लेखक के पास मौजूद है. शैली और अभिव्यक्ति भी, जो कौशलगत प्रभाव उत्पन्न कर सकने से अलग समूची कृति में अपनी रचनात्मकता की साख बनाए रखती है वह यकीनन इस उपन्यास की विशेष प्राप्ति है.

माड़ी की ड्योढ़ी में से गुजरते हुए पाठक को लेखक की मितव्ययिता का आभास बराबर होता चला जाता है. जिस दृष्टि की यह अभिव्यक्ति है वहां अंतर्द्वंद्व नहीं फैसला है, निर्णय है. आंखों के आगे से सरकने सरकाने की कोशिश, आहट भी पात्रों के हक में इतनी ही कि बोलने वाला खुद को भी न सुन सके— सिर्फ दिल पर लिखी इबारत के अक्खर बांच सके, बिना आवाज के चुपचाप. उपन्यासकार ने अपनी क्षमताओं के बल पर स्वयं को खटखटाने हेतु 'लोक' का जो संसार 'माड़ी' में बुना है वह दरअसल लेखक के अपने स्मृति पटल पर आरपार फैला है. 'तमस' के ठीक विपरीत राजनीति का जुनून दीवानों की पगड़ियों पर से गायब है और ऐतिहासिक घटनाचक्र भी इतना ही कि कथावाचक खुद सुने और खुद ही देख भी सके. जनसाधारण के प्रसंग और रोजमर्रा के विवरण कुछ ऐसी पीड़ा और कचोट देते हैं कि जैसे उन्हीं की जमीन से उन्हें ही बेदखल हो जाना हो. व्यतीत हो जाने की, धूल हो जाने की गहरी व्यथा समूचे उपन्यास में इकहरेपन से व्याप्त है. मय्यादास की माड़ी न संघर्ष करने को खड़ी है, न विद्रोह और न इंकलाब करने को. सूखी लकड़ी के चरमराते पुराने किवाड़ों की तरह चरमराकर खामोश ही हो जाती है. पुराना ढांचा झुरमुरा रहा है. फिरंगी का जुग रेलगाड़ी के पहियों पर धड़धड़ा चला आता है. इस समूचे नेपथ्य का संचालन सात समुद्र पार से हो रहा है. यही रौंदता चला जाएगा माड़ियों, महलों और झरोखों को आने वाले कल के, भविष्य के सौ बरस देखेंगे इस इतिहास की कड़ी को, मय्यादास की माड़ी को. इन दोनों के बीच का गलियारा उपन्यासकार क्यों खोल नहीं पाया— शायद अपनी कुंजी को खोलने न खोलने का अधिकार उसे है. हां इन पन्नों में बिखरी, फैली, बूढ़ी परछाइयां सैनिक टुकड़ियों को जरूर सिर धुनते देख रही हैं.

> **"सवाल देशप्रेम या देशभक्ति का नहीं था. सवाल नमकहलाली का भी नहीं था, वफादारी का भी नहीं था. सवाल केवल अपने हित का था. किस ओर कदम उठाएं कि बच भी जाएं और कुछ प्राप्ति भी हो जाए"**
>
> इसी किताब से

इतिहास के साक्ष्य को परेशानी होती है यह जानकर कि पठान मुगल नजीब और खालसी की सैनिक टुकड़ियों में से एक बहादुर पात्र भी क्यों न उठ खड़ा हुआ और शहीदी की परंपरा में शामिल होने की सामर्थ्य भी क्यों न जुटा पाया. पराधीन होने की यंत्रणा, यातना में से कुछ तो ऐसा समोया ही जा सकता था जो देशीय स्वाभिमान की पताका को आखिरी बार, एक बार फहरा सकता. देशभक्ति के नाम पर दीवानों की टुकड़ा-टुकड़ा होती अमलदारी जो खालसा राज में राजसी बंदोबस्त की भागीदार थी, बेबस और तीन लड़कियां लड़कर हथियार डालने के कलंक को धो सकती थी. 'टोड़ी' और 'अटोड़ी' दलों की सामाजिक और राजनैतिक जागृति के मिले-जुले रूप में इतनी बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का सहज सरलीकरण इतिहास के किसी भी पाठक को अखरेगा.

खोई हुई अस्मिता के लुटे-पुटे चिन्ह टट्टू और उन पर सवारी करते रखैलों के बेटे क्या सचमुच इतिहास की नियति के बाहर थे? पराजय की इतनी गहरी छटपटाहट में से सिर झुका देने से पहले स्वाभाविक साहसिकता की ओर भी क्यों न देख लिया गया? क्या तात्कालिक अनुभव के आतंक ने एक बुढ़ाती जीवन शैली के प्रामणिक परिवेशों तक को नकार दिया था?

सच यह भी है कि जिन बुनियादी सवालों को हल करने का बीड़ा भीष्म साहनी ने मय्यादास की माड़ी में उठाया, उसे उन्होंने सफलतापूर्वक अपने ग्राफ के मुताबिक आश्चर्यजनक पैनेपन से अंकित भी कर दिखाया. सामंती अमलदारी मात्र धूर्तता और कांइयापन की ही प्रतीक नहीं थी. स्वयं मय्यादास की माड़ी के पात्र इसके प्रमाण हैं. वीरांवाली, ईशरदयी, रुक्मो, पुरोहित रामदास, दीवान धनपत राय, मंसाराम, कल्ला, लेखराज, भागसुद्दी बांशी, रामजवाया माड़ी में चलते-फिरते, जीते-जागते लोग हैं. उनकी पहचान देने वाली आंख भीष्म की है जिसने 'लोक' को वैज्ञानिक ढंग से अरखा-परखा है और उसे सफ़ा-दर-सफ़ा पेश किया है. "दीवान हुकूमतराय अंत में पतलून उतारने में कामयाब हो गया था. पतलून को फर्श पर ही फेंककर सिर पर पगड़ी पहने-पहने ही वह पलंग पर दराज हो गया था. सोने से पहले उसके दिल में फिर से गुदगुदी-सी हुई. वह बुदबुदाया— रायबहादुर-रायबहादुर और करवट बदलकर नींद में खो गया."

—हरमहिंदर चहल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सही निर्णय का

अन्दरूनी राज़

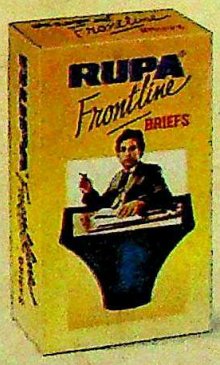

प्रश्न जब त्वचा की सुरक्षा का है, तो सावधानी बरतने में ही समझदारी है। गलत निर्णय आपके लिये परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिये रूपा फ्रन्टलाइन ही खरीदिये और निश्चित रहिये। भारतीय जलवायु के उपयुक्त, नवीनतम तकनीक से बना रूपा फ्रन्टलाइन आपकी त्वचा को बराबर सुरक्षा देता है।

शतप्रतिशत सुती धागे से बना। इसकी उत्कृष्ट फिनिश रेशम सी कोमलता का अहसास दिलाये। फिटिंग पूर्णतः आरामदायक। इम्पोर्टेड रबर से बना इलास्टिक। निराले रंगो में उपलब्ध। इन्हीं सब खूबियों के कारण रूपा फ्रन्टलाइन सही निर्णय लेने में आपका सहायक होता है।

RUPA®

Frontline

BRIEFS

'फ्रन्ट ओपन' की स्पेशल सुविधा सिर्फ रूपा फ्रन्टलाइन ब्रीफ़ में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भारत में पहली बार, अपनी किस्म का खास

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

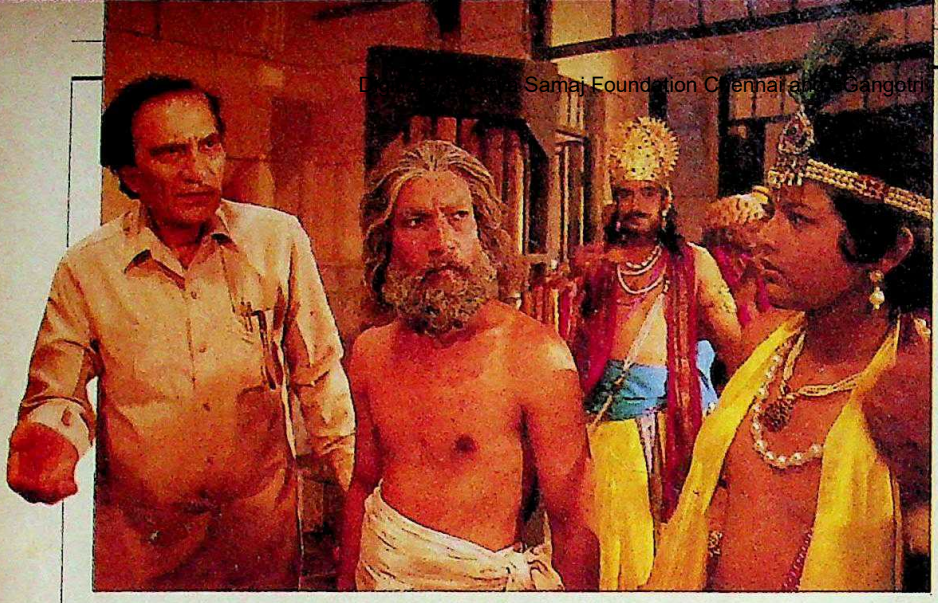

'महाभारत'

छोटे परदे पर बड़ी लड़ाई

धारावाहिक के पहले प्रकरण से ही लोगों की दिलचस्पी बढ़ी

महीनों की बहस, विवादों और अंदेशों का आखिर अंत हुआ. और 'महाभारत' का पदार्पण अंततः टीवी के परदे पर हो ही गया. ऐसे महाकाव्यों के धारावाहिक पर विवाद और असंतोष की जो परंपरा रही है वह इस धारावाहिक में भला कैसे टूट सकती थी. बी.आर. चोपड़ा के इस भव्य धारावाहिक के पहले ही प्रकरण में अटकलों की शुरुआत हो गई है.

महाभारत की कथा गंगा के प्रति महाराज शांतनु के प्रेम से शुरू होती है. शांतनु उसे देखते ही उसके प्रेमपाश में बंध जाते हैं. हस्तिनापुर महाराज का यह अंधा प्रेम भाई-भाई में कलह के बीज बो देता है. महाभारत की कथा भाइयों के इसी कलह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी परिणति कौरव कुल के नाश में ही होती है.

लेकिन चोपड़ा महाभारत की कथा थोड़ा और पीछे से शुरू करते हैं. राजतंत्र के बारे में महाराजा भरत की आदर्शवादी अवधारणाओं से धारावाहिक शुरू किया गया. किंवदंती के अनुसार भरत ने अपने नौ पुत्रों में से एक को भी हस्तिनापुर के सिंहासन के योग्य न पाकर अपने वंश के बाहर के व्यक्ति भूमन्यु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था. कई पीढ़ियों बाद महाराजा शांतनु ने परंपरा को तोड़कर गृह कलह के बीज बोए. और परिणाम कुरुक्षेत्र के युद्ध के रूप में सामने आया. अपने धारावाहिक के पहले ही प्रकरण में भरत की विलक्षण राजनैतिक सदाशयता और शांतनु की असफलता का विरोधाभास दिखाकर चोपड़ा ने 'महाभारत' के एक अहम सूत्र को रेखांकित कर दिया है. वह सूत्र है—सत्ता की वैधता का.

कृष्ण की भूमिका में नितेश भारद्वाज

महाभारत के सेट पर चोपड़ा (एकदम बाए

एक ही खूबसूरत कलाकारी से चोपड़ा 'महाभारत' रामानंद सागर की 'रामायण' मुकाबले न केवल ज्यादा समसामयिक गया है बल्कि राजनैतिक अर्थों में विस्फो भी. इस उपमहाद्वीप के कुछ देशों में आधुनिक किस्म का वंशवाद चल रहा उसके संदर्भ में यह बहस निश्चित ही दि चस्प होगी कि सत्ता पर परिवारवाद हा रहे या योग्यता. ज्यादातर दर्शकों को इस नेहरू परिवार का ख्याल आएगा ही.

फिल्मी अभिनेता राज बब्बर अगर भर की भूमिका में हों तो जाहिर है कि माम और दिलचस्प बनेगा. अब सवाल यह उठा जा रहा है कि क्या दूरदर्शन ने इस धारा- वाहिक की पहली कड़ी में किए गए राज नैतिक कटाक्षों के डर से इसके कुछ अंश काट देने का निर्देश चोपड़ा को दिया था? किसने यह निर्देश दिया था? दूरदर्शन के तत्कालीन महानिदेशक भास्कर घोष ने या सूचना प्रसारणमंत्री हरकिशनलाल भगत ने या जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने?

दूरदर्शन सूत्रों का कहना है कि इस धारावाहिक के कुछ शुरुआती प्रकरणों को घोष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने देखा था. चोपड़ा भी कहते हैं कि ये अंश संपादन के दौरान ही काटे गए, न कि दूरदर्शन के आदेश

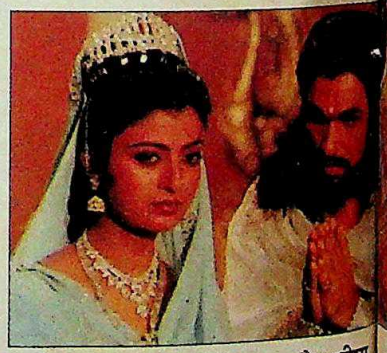

सत्यवती बनीं देवाश्री राय और भीष्म की भूमिका में मुकेश खन्ना; (नीचे) अरुण शुक्ला महाराज शांतनु की भूमिका में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"हमारा मकसद किसी की किसी से ...ना करना या कटाक्ष करना नहीं है, बल्कि ...ों को महाभारत की कथा दिखाना है."

बहरहाल, धारावाहिक के पहले प्रकरण में ...न के दरबार के बाद सीधे राजमाता ...ना के कक्ष का दृश्य और भरत के ...न के बाद सीधे शांतनु के दृश्य जिस तरह ...किए गए हैं उनसे साफ लगता है कि बीच ...य बड़ी बेतरतीबी से काटे गए हैं. काटे ...ने पहले इस भाग में दिखाया गया है कि ...को राज सिंहासन न देने के अपने निर्णय ...ट करते हुए भरत कहते हैं, "राजा का ...राज्य के हितों की रक्षा करना है न कि ...वों के हितों की."

...ले दो प्रकरणों में दिखाया गया है कि ...न शांतनु योग्य व्यक्ति को ही राजा ...ने की राजा भरत की आदर्शवादी ...जारी रखने में किस तरह असफल ...हैं. इस तरह शांतनु के राज्य के दुर्दशा ...ने वाले चौथे प्रकरण के कुछ दृश्यों को ...के आदेश भी दूरदर्शन ने दे डाले.

...धारावाहिक के पटकथा लेखक राही ...रजा मानते हैं कि राजनैतिक वैधता ...साल महाभारत के मूल कथ्यों में से एक है. धारावाहिक की शुरुआत राजा भरत के प्रसंग से करने के निर्णय के बारे में वे बताते हैं, "भरत को दिखाए बिना हमें कथा का मूलाधार नहीं मिल पाता. वे एक ऐसा राजनीतिक वक्तव्य दे डालते हैं जो रामायण काल से भी पहले का विचार है—"सत्ता का अधिकार जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है. आज देश की राजनैतिक परिस्थितियां कुछ-कुछ महाभारत काल जैसी ही हैं."

जो हो, 'महाभारत' भी 'रामायण' की तरह ही दर्शकों को अपने जादू में बांधने में जरूर सफल होगा, हालांकि इसका कथानक धार्मिक न होकर लौकिक है. लेकिन चोपड़ा के सामने एक बड़ी दिक्कत है—'रामायण' में तो ढेरों देदीप्यमान पात्र हैं लेकिन महाभारत में अकेले श्रीकृष्ण ही हैं. महाकाव्य 'महाभारत' में कृष्ण वयस्क रूप में ही नजर आते हैं. एक संपूर्ण मानव, योद्धा, दार्शनिक और कर्मयोगी के रूप में. धारावाहिक के सह-निर्देशक और बी.आर. चोपड़ा के पुत्र रवि चोपड़ा कहते हैं, "कृष्ण के बिना तो महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती. ऐसा नहीं है कि हम उन्हें खास तौर से ज्यादा तरजीह दे रहे हैं."

चोपड़ा ने कृष्ण की भूमिका के लिए मराठी रंगमंच और फिल्मों के अपेक्षाकृत अपरिचित कलाकार—25 वर्षीय नितेश भारद्वाज को चुना है जो पेशे से पशु चिकित्सक हैं. नितेश कहते हैं, "महाभारत में कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल पात्र हैं. वे भारत में लोकतंत्र के अग्रदूत थे. मुझे लगता है कि मुझ पर एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है."

27 नवंबर से धारावाहिक 'रामायण' का 26 प्रकरणों वाला दूसरा खंड भी दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा. तभी यह निर्णय हो पाएगा कि दर्शकों के दिल और दिमाग पर कौन राज करता है—सागर या चोपड़ा.

और इस तरह अगले महीने से दर्शकों को हर इतवार की सुबह छोटे परदे पर कई 'बड़ी लड़ाइयां' देखने को मिलेंगी—देवताओं और मनुष्यों के बीच, फिल्म निर्माता से धारावाहिक निर्माता बने फिल्मकारों के बीच, और विज्ञापनदाताओं के बीच. दूरदर्शन पहले प्रकरण से पहले दिखाए जाने वाले 10 सेकेंड के विज्ञापन के लिए 65,000 रुपए वसूल कर रहा था. यह अब तक कि सबसे ऊंची दर है. शुरू में तो धारावाहिक के हर प्रकरण से 25 लाख रु. से ज्यादा की ही आमदनी होगी. 78 प्रकरणों वाले 'रामायण' के पहले खंड से दूरदर्शन ने लगभग 18 करोड़ रु. कमाए. अब दो धारावाहिकों के इतने ही प्रकरणों (जिनमें रामायण के 26 और महाभारत के 52 प्रकरण हैं) से भी दूरदर्शन इतनी ही कमाई करने की उम्मीद रखता है. भरत ने राज करने के अधिकार के बारे में चाहे जो भी कहा हो, नकदी तो अंततः राज्य की ही झोली में पहुंचने वाली है. —एम. रहमान

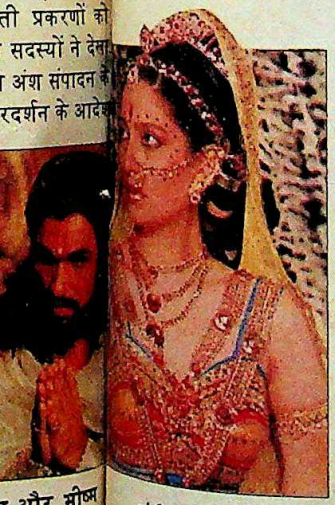

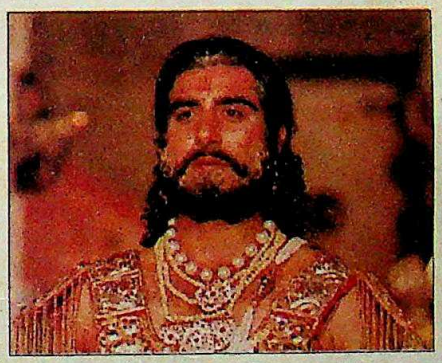

कुंती की भूमिका में नाजनीन (ऊपर बाएं); राजा भरत बने राज बब्बर; और (नीचे) गांधारी की भूमिका में रेणुका इसरानी, नाजनीन, विदुर बने राजदान और पांचों पांडव

शकुनि की भूमिका में गुंफी पेंटल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिप्सा मक्कड़: नन्ही चालक

◆ वह जहां जाती है, सड़कें जाम हो जाती हैं. पर उम्र उसकी महज पांच साल है. ढाई फुट की **जिप्सा मक्कड़** बेशक अभी केजी में ही पढ़ती है लेकिन कार वह मंजे चालक की तरह चलाती है. हाल ही में उसने रोहतांग दर्रे से मनाली तक के 55 किमी मार्ग पर कार चलाकर औरों के अलावा पुलिसवालों को भी हैरत में डाल दिया और वे उसका चालान तक करना भूल गए. जिप्सा ज्यादातर मारुति चलाती है. वह और भी ऊंचा उड़ना चाहती है. अक्सर वह अपने पापा से पूछती है, "मैं हवाई जहाज कब उड़ा सकूंगी?" रिकार्ड देखकर लगता है यह इच्छा पूरी होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा.

प्रशांत पंजियार

प्रशांत पंजियार

शेफालिका (इनसेट); 'बॉस' के साथ नाचते हुए

◆ मानवाधिकारों के लिए संगीत कार्यक्रम में रॉक संगीतकार ब्रूस स्प्रिंग-स्टीन ने अपने दावे के मुताबिक दिल्लीवासियों को सचमुच झूमने की मुद्रा में ला दिया. पर आयोजन के दौरान पूरे पांच मिनट **शेफालिका मिश्र** ही छाई रहीं. मौर्य होटल की इस 18 वर्षीया खूबसूरत प्रशिक्षार्थी को उस रात के शो के लिए स्प्रिंगस्टीन ने चुना था. जब वे 'बॉस' के साथ आई तो 60,000 दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खुशी जाहिर की. 'बॉस' के साथ 'डांसिग इन द डार्क' का कैसा अनुभव रहा? इस पर उनकी चहेती का जवाब था, "जैसा किसी सुंदर पुरुष के संग नाचने पर होता है." और स्प्रिंग-स्टीन के चुंबन के बारे में इस 5 फुट 5 इंच सुंदरी का कहना था, "वह सचमुच लाजवाब था."

◆ रक्षामंत्री का बेटा और जेल में! **सुनील पंत** को सचमुच पूरा दिन जेल में बिताना पड़ा. उन्होंने माना कि यह वाकई उनके जीवन की सबसे यादगार घटना है. वे प्रसिद्ध फिल्मकार प्रकाश झा के टीवी धारावाहिक 'मोमेंट्स' में गोविंदवल्लभ पंत के शुरुआती

'मोमेंट्स' में सुनील पंत: दादा जी को श्रद्धांजलि

आलोक श्रीवास्तव

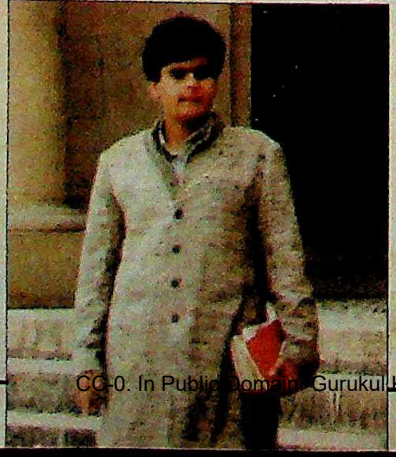

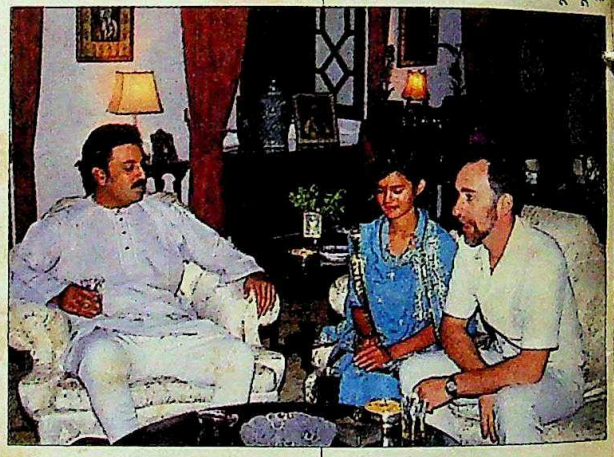

महाराजा (बाएं) के साथ शेफाली और उसके पिता

जीवन की भूमिका निभा रहे हैं. दिल्ली के सेंट स्टीफन में पढ़े सुनील कहते हैं, "यह भूमिका मुझे सहज ही मिल गई." मिलती भी क्यों नहीं, उन्हें अपने दादा का किरदार ही तो निभाना है. वे कहते भी हैं, "उन्हें मेरी यही श्रद्धांजलि है."

◆ जमीन पर उतरने के भी कई उपाय हैं. जी हां, अंतरिक्ष से उतरने वालों के लिए भी. हाल ही में भारत के मशहूर अंतरिक्षयात्री **राकेश शर्मा** को ऐसा ही कष्टप्रद अनुभव हुआ है. नासिक के नजदीक अभ्यास उड़ान के दौरान शर्मा मिग-21 विमान से कूदे तो उनका पैराशूट एक हल्के बिजलीयुक्त तार में फंस-कर जमीन पर आ गिरा और वे बाल-बाल बचे. पर उनके बाएं पैर का टखना टूट गया. फिलहाल पुणे के एक निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा है. हर क्षेत्र के लोग उन्हें देखने पहुंचते रहते हैं. बहरहाल, इस हादसे से शर्मा के विनोदी मिजाज पर कोई असर नहीं पड़ा है. पैराशूट के बारे में उनका कहना था, "वह तो तंबू बन गया होगा."

◆ सपने भी कभी सच होते हैं! **शेफाली बेट्स** का तो यही अनुभव है. बांग्लादेश से गोद ली हुई 11 वर्षीया यह बच्ची राजकुमारी बनना चाहती थी. ब्रिटेन की राज-कुमारी डायना जैसी नहीं बल्कि एक अदद भारतीय राजकुमारी की तरह, "क्योंकि वे ज्यादा खूबसूरत होती हैं." इसलिए उसने बीबीसी के 'फिक्स इट' कार्यक्रम की प्रसिद्धि वाले जिम सेविले को चिट्ठी लिखी. और पिछले सप्ताह उसे महाराजा गज सिंह के अतिथि के रूप में जोधपुर के उमेद भवन राजप्रासाद में शाही ठाट-बाट का स्वाद चखने को मिल ही गया. प्रसन्नचित 'राज-कुमारी' ने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सचमुच संभव भी हो सकता है."

सुरेंद्र मलहोत्रा

राकेश शर्मा: आकाश से गिरे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया दौर, नई जिम्मेदारी

लंबे अरसे बाद पाकिस्तान में जम्हूरियत का जलवा दिखाई पड़ा है. बेनजीर भुट्टो को पूर्ण बहुमत भले ही न मिल पाया हो पर वे ही अवाम की उम्मीदों का मरकज़ बनकर उभरी हैं. सत्ता पीपुल्स पार्टी के चरण चूमने जा रही है पर वक्त की कसौटी पर उसकी परख बाकी है.

आवरण कथा.....24

ओछा अभियान, घटिया जुमले

चुनावों की संभावनाओं के मद्देनजर बोफोर्स का विवाद एक बार फिर उभरने लगा है. लेकिन तथ्य सामने लाने और स्वस्थ बहस चलाने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता विषवमन और एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुट गए हैं.

खास रपट.....14

एक इम्तिहान में कामयाब

श्रीलंका में प्रांतीय परिषद के लिए बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुए चुनाव भारत-श्रीलंका समझौते को अमल में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसने समझौते के विरोधियों का मुंह बंद करके तमिलों की अगुआई वाली सरकार कायम होने की राह खोल दी है.

पास-पड़ोस.....84

महाराजा से छेड़खानी

एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन जेतली ने 'महाराजा' को नई छवि देने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव का अभियान चलाया तो कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ दिया. पर अंशकालिक अध्यक्ष रतन टाटा और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी अभी भी जेतली के तौर-तरीकों से नाखुश हैं.

उड्डयन.....91

हवाई हादसों को अभिशप्त

भारतीय वायुसेना में दुर्घटनाओं की दर भयानक हदें छूने लगी है. महज़ दस दिनों में पांच मिग-21 लड़ाकू विमान ध्वस्त हो जाने से इस विमान की क्वालिटी, रखरखाव और उसे चलाने के तौर-तरीकों को लेकर कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. खोजपरक रिपोर्ट:

प्रतिरक्षा.....94

रुमानी दुनिया की ओर उड़ान

विज्ञापनबाजी ने सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति मध्यम व संपन्न तबके की महिलाओं के सोच को नया मोड़ दे दिया है. नतीजतन, आज इन घरों में ड्रेसिंग टेबल की शोभा बढ़ाने वाली और महिलाओं के चेहरों को नया निखार देने वाली सामग्रियों में बदलाव आया है.

रहन-सहन.....110

कसौटी.....7
तेवर.....8
राजरंग.....10
हिंदोस्तां हमारा.....11
बीता पखवाड़ा.....13
खास रपट
राजनैतिक माहौल:
ओछा अभियान, घटिया जुमले.....14
भारत-रूस संबंध: बदलाव की प्रक्रिया.....18
आवरण कथा
बेनजीर भुट्टो: नया दौर, नई जिम्मेदारी..24
आजकल
विपक्ष: अंजाम से दूर अफसाना.....34
बिहार: चोले की फिक्र.....37
तमिलनाडु: बचाव में हमला.....43
कर्नाटक: विजयी बोम्मई.....44
हरियाणा: घृणित साजिश.....45
बात पते की.....47
खास रपट
भोपाल गैस हादसा:
नाउम्मीदी का आलम.....48
राज्य-दर्पण.....61
खास रपट
केरल: मोर्चे को कई मोर्चों पर चुनौती.....62
व्यापार चक्र.....65
कारोबार
डीसीएम: बंटवारे की
उत्सुकता आखिर रंग लाई.....66
मूंगफली: तेल की धार.....69
कोका कोला: घुसने की तैयारी.....75
वाणिज्य वार्ता.....77
विज्ञान
परमाणु ऊर्जा: विवादास्पद समझौता.....78
विकास
आंध्र प्रदेश: प्रचार का जादुई नुस्खा.....81
पास-पड़ोस
श्रीलंका: एक इम्तिहान में कामयाब.....84
परदे के उस पार.....89
उड्डयन
एअर इंडिया: महाराजा से छेड़खानी.....91
प्रतिरक्षा
भारतीय वायुसेना:
हवाई हादसों को अभिशप्त.....94
खेलकूद
पी.टी. उषा: नाकामी, लानतों का दुख.....97
सिनेमा
आमिर खां: कयामत की मासूमियत.....98
धर्म
भगवती जागरण:
भक्ति राग नहीं, रॉक भक्ति.....100
रंगमंच
साधारण लोग: ढोंगी राजनीति बेनकाब.102
स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश: वृद्धाओं की वेदना.....103
पर्यावरण
नैनीताल: खिसकती चट्टानों की चोट.....105
किताबें.....107
रहन-सहन
प्रसाधन सामग्री:
रुमानी दुनिया की ओर उड़ान.....110
चर्चित चेहरे.....112

आवरण: भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

टाइल्स का ये रोमानी संसार

स्पारटेक सनसनी

आकर्षक नया साइज़
३०५ मि.मी. x १५२.५ मि.मी.

पेश है
रेनसांग सिरीज़

पानी की बूंदों सी थिरकन, नर्म, मुलायम, प्यार का अहसास जगाती
रेनसांग, टाइल्स से बरसे रिमझिम का संगीत. स्पारटेक रेनसांग सिरी
तीन हलके मनमोहक रंग, हर दिल में जगाएं प्यार की नई उमंग!

स्पारटेक

५२, चैमियर्स रोड, मद्रास ६०० ०२८.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब मशहूर रंगीन टी वी की दुनिया में

चैम्पियनों का चैम्पियन

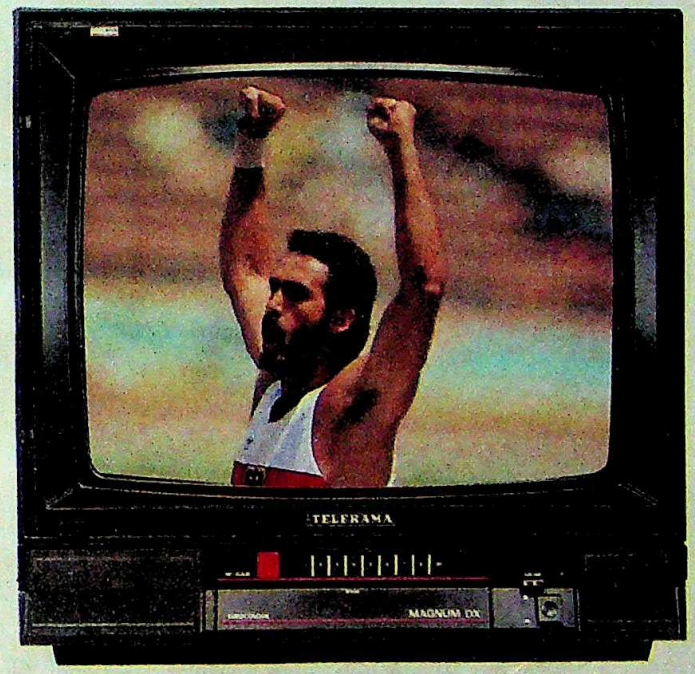

TELERAMA
MAGNUM DX HI-GAIN

दो साल की गारंटी पिक्चर ट्यूब सहित

नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय रूप। सम्पूर्ण काला और फिनिश चिकनी। हू-ब-हू रंग सहित जीवन्त तसवीर। दो-तरफा स्पीकर—जिसमें क्रॉसओवर नेटवर्क तकनीक की वजह से आवाज़ भी जानदार। कम्प्यूटर की मदद से तैयार, इसलिए काम की क्वालिटी लाजवाब और निर्भरयोग्यता की भी पूरी निश्चयता। दूर हो या पास-हाई-गेन की देन स्पष्ट और शानदार तसवीर। मैगनम DX यूरोकलर टी वी—देखने में आराम, रखने में शान।

टेलेरामा मैगनम DX हाई-गेन टी वी। यकीन कीजिये—यही है चैम्पियनों का चैम्पियन!

It's the smart choice

3337A2

अपने करीबी डीलर के पास इसके दमखम की जाँच कीजिये...
सचमुच, यह सबको मात देगा।

TELERAMA AUTHORISED SERVICE CENTRE FOR ITT COLOUR TVs

पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, असम, उत्तर-पूर्वी राज्यों, पूर्वी मध्य प्रदेश तथा बंगलौर शहर में उपलब्ध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लीडर की गारंटी

नकल से दुहरी सुरक्षा

हरचंद कोशिशों के बावजूद हम ड्यूरोबोर्ड की नकल एकदम रोकने में सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हमने प्रत्येक ड्यूरोबोर्ड पर आपके जाने-पहचाने लेबल के साथ एक स्ट्रिप भी लगा दी है। ध्यान दीजिये कि आप जो ड्यूरोबोर्ड खरीद रहे हैं उस पर वे दोनों है।

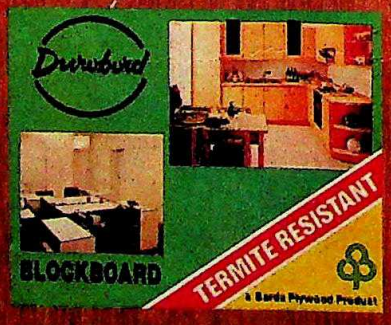

Durobord®

असली नं-१

ड्यूरो-
ब्लॉकबोर्ड का हीरो

सारदा प्लाइवुड
इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

वर्क्स: जेपुर (आसाम)
जनरल सेल्स ऑफिस:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 3, अंक: 3, 1-15 दिसंबर, 1988

प्रधान संपादक
अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक
प्रभु चावला

संपादकीय विभाग
जगदीश उपासने, अशोक कुमार, विजय क्रांति, ओम प्रकाश सराफ, अरविंद मोहन मिश्र

प्रोडक्शन
अनिल शर्मा, सुबाचन यादव
सुनील सैनी

■ **संपादकीय कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली.

■ **मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:** इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

■ **मुख्य विज्ञापन कार्यालय:** 28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया, बंबई.

■ **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** के-9, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली • फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास • 74/1 सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर • 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता. • कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता. • लिविंग मीडिया इंडिया लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

नेपाल में 7 रुपए

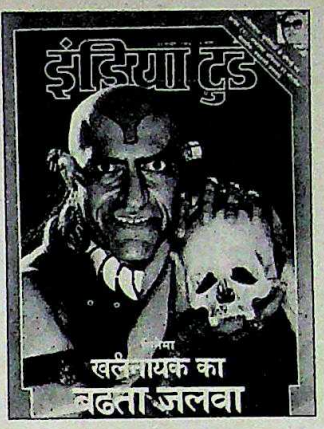

समाज का आईना

'खलनायक का बढ़ता जलवा' (30 नवंबर) नई पीढ़ी की मानसिकता और समाज के बदलते नैतिक मूल्यों का ही चित्रण है. लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि ऐसी फिल्में पसंद करने वाली पूरी पीढ़ी ही भ्रष्ट है. दरअसल खलनायक से जुड़ी सत्ता, वैभव और ग्लैमर में वे अपनी दबी आकांक्षाओं को ही साकार पाते हैं.

—**राजेंद्र सिंह,** नई दिल्ली

■ समाज में बढ़ती हिंसा और चमक-दमक के लिए दीवानगी इस तरह की फिल्मों की ही देन है. इस स्थिति में यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि समाज फिल्मों से प्रभावित होता है या फिल्में समाज का आईना होती हैं.

—**प्रमोद कुमार,** बागपत (उ.प्र.)

नजरिया बदलें

'विवेक पर हावी वोटों का लोभ' (30 नवंबर) राजनीति को धर्म से अलग न रखने का ही दुष्परिणाम है. जिस तरह इन सांप्रदायिक दंगों की आग में राजनीतिक अपने स्वार्थ की रोटियां सेंकने में लगे हैं, उससे तो यही लगता है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनकी तमाम घोषणाएं नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं हैं.

—**क्षिप्रा,** नई दिल्ली

■ जब तक धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, दंगे इसी तरह जारी रहेंगे. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इस नजरिये तो सुलझाया नहीं ही जा सकता है, उलटे कई और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.

—**निम्मी,** आगरा (उ.प्र.)

उपेक्षा का नतीजा

हृदय विदारक विमान दुर्घटनाओं पर आवरण कथा 'घरेलू विमान यात्रा: भाग्य भरोसे?' (15 नवंबर) पढ़कर यही महसूस हुआ कि शायद देश में घरेलू विमानों के लिए उड्डयन विभाग की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है. अहमदाबाद के नजदीक ध्वस्त हुआ बोइंग-737 विमान तो एक डैने तथा और भी कई यंत्रों के बिना ही उड़ानें भरता था. क्या 18 साल पुराने जर्जर विमान को बदलने की जिम्मेदारी उड्डयन विभाग की नहीं है?

—**नवनीत कुमार,** दरभंगा (बिहार)

■ एअरलाइंस के प्रबंध निदेशक गैरी पाइस से बातचीत बेहद बचकाना और गैर-जिम्मेदारी भरी लगी. 'रोजाना 270 उड़ानों के प्रबंध...' जैसे वक्तव्यों की आड़ में सचाई को नकारना अच्छे प्रबंधक की निशानी नहीं.

—**संजीव पुरोहित,** दतिया (म.प्र.)

■ आपकी पत्रिका में पहली बार विमान दुर्घटनाओं के कारणों पर इतनी विस्तृत जानकारी पढ़ने को मिली. लेकिन इनसे कहीं ज्यादा विमान दुर्घटनाएं वायुसेना के विमानों से होती हैं जिनके कारणों की न कभी जांच होती है, न तो जिनकी विस्तृत रिपोर्ट ही छापी जाती है. क्या वे राष्ट्रीय संपत्ति नहीं हैं?

—**एक तकनीकी वायु सैनिक,** चंडीगढ़

वोट बैंक की चिंता

कसौटी 'फिर वही कछुआ वृत्ति' (15 नवंबर) में आपने एकदम ठीक लिखा है कि 'द सैटनिक वर्सेस' और 'द लास्ट टेंपटेशन' पर प्रतिबंध सरकार द्वारा अपने 'वोट बैंक' को खुश रखने का ही तरीका है. कुछ अरसे पहले रुश्दी साहब पर मुस्लिम एजेंट होने का आरोप लगाया गया था और अब उन्हें इस्लाम की मान्यताओं पर आघात करने का अपराधी बनाया गया है. सलमान रुश्दी ने यह निर्णय लेकर अच्छा ही किया कि वे अब भारत पर कभी कुछ नहीं लिखेंगे.

—**भीलू,** बाड़मेर (राज.)

■ यह भी हैरानी की बात है कि जिस पुस्तक को पुरस्कार योग्य समझा जा रहा है उस पर इस्लामी देशों से पहले पाबंदी लगाकर हमारी सरकार ने अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित कर दी.

—**राजीव गोगेगावे,** नांदेड़ (महाराष्ट्र)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पक्षपातपूर्ण वक्तव्य

मौलाना आजाद द्वारा लिखे पृष्ठों के अंश 'भयंकर भूलों की करुण कथा' (15 नवंबर) पक्षपातपूर्ण लगी. माना कि बंटवारा नेहरू और पटेल की भूलों के कारण हुआ किंतु आजाद तब चुप क्यों रहे. उन्होंने और गणमान्य नेताओं ने कैबिनेट मिशन योजना की नामंजूरी और बंटवारे के विरोध में अपना बयान क्यों नहीं दिया. दर-असल बंटवारे का कारण कुछ व्यक्ति विशेष नहीं थे, बल्कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि विभाजन अपरिहार्य हो गया था.

—**प्रेमेंद्र गंधार,** इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ मौलाना आजाद के दस्तावेज पढ़कर एक किस्म का आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ कि देर से ही सही जनता के सामने एक ऐतिहासिक सच तो प्रकट हुआ.

—**ठाकुर नरसिंह राजा,** गुलबर्गा (कर्नाटक)

■ यह कहना कि 'बंटवारा नेहरू की नादानियों की वजह से हुआ' हास्यास्पद ही है. अभी उस पीढ़ी के लोग जिंदा हैं जिन्हें मालूम होगा कि बंटवारा किन हालात में हुआ था. फिर आजाद की पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' ज्यों की त्यों छपवाने के लिए नेहरू ने ही जोरदार पैरवी की थी. बाकी सभी नेता इसके खिलाफ थे.

—**बीरबल शर्मा,** कच्छ (गुजरात)

सही आकलन

खास रपट 'उलझन और त्रासदी' (15 नवंबर) पढ़ी. 700 बहादुर सैनिकों की बलि देकर भी भारत के हिस्से शक और संदेह ही आया है. इस तरह स्पष्ट नीति और दूरगामी चिंतन के अभाव में एक नेक इरादा रणसिंघे प्रेमदास और सिरिमाओ भंडारनायके जैसे पार्टी नेताओं के चुनाव प्रचार का मुद्दा बन गया है. उचित यही होगा कि भारत पड़ोसी देशों के प्रति अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करे.

— **अर्चना सिन्हा,** इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ जल्दबाजी में किए समझौते ने अच्छे-भले मित्र देश को अपना दुश्मन बना लिया है. भारतीय शांति सेना जिस दुरूह स्थिति में वहां रह रही है और जिस तरह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उसकी वापसी को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं उससे स्पष्ट है कि हमारे सैनिकों का बलिदान और आर्थिक सहायता व्यर्थ ही गई.

—**विजय मेहरा,** रतलाम (म.प्र.)

बेटों के सामने बौने

'दो लालन के बीच में' (15 नवंबर) पढ़कर लगा कि हरियाणा के मुंहफट व दबंग मुख्यमंत्री देवीलाल अपने ही पुत्रों के सामने कितने बौने हैं, अन्यथा अपने बड़े बेटे की धमकी के आगे झुकने और इस्तीफा देने का स्वांग रचने की क्या जरूरत थी.

—**ताराचंद नागर,** श्रीगंगानगर (राज.)

जागरूकता की निशानी

किसानों ने 'राजपथ पर दस्तक' (15 नवबर) देकर सरकार को यह एहसास करा दिया है कि वर्षों से मूर्ख और अनपढ़ समझे जाने वाले किसान अब जागरूक हो गए हैं. भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की उपेक्षा दुखद ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकर भी है.

—**वीरेंद्र प्रताप सिंह,** गोरखपुर (म.प्र.)

यदि आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए

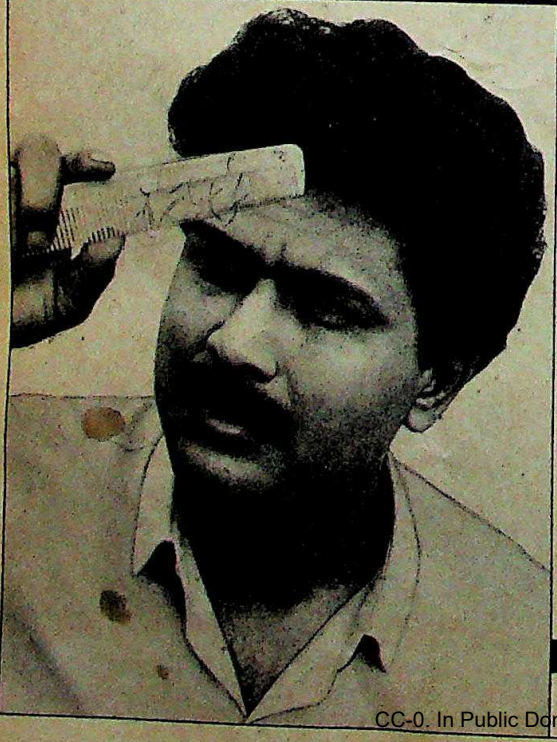

२५ साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के बाल झड़ रहे हैं.... लेकिन उन्हें इसका पता नहीं!

क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आज ही यह परीक्षण कीजिए.
अपने बालों को ज़ोरों से कंघी कीजिए. अगर कंघी पर बाल उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं.

इसका हल है — प्योर सिल्विक्रिन
बालों के झड़ने का कारण है — ज़रूरी अमिनो एसिड्स की कमी — जो आपके बालों की कुदरती ख़ुराक हैं. केवल प्योर सिल्विक्रिन में ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है जो इस कमी को पूरा करता है.
इसके कारण हैं :

१. प्योर सिल्विक्रिन १७ अमिनो एसिड्स का अनोखा मिश्रण है — आपके बालों की कुदरती ख़ुराक.

२. रेडियो ट्रेसिंग का प्रयोग करने वाली विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि प्योर सिल्विक्रिन, बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी पहुँचती है, बालों में कुदरती ख़ुराक की कमी पूरी करती है और बालों को फिर से स्वस्थ बनाती है.

उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की त्वचा पर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का स्वास्थ्य सामान्य नहीं हो जाता.

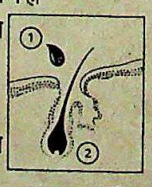

जल्दी कीजिए! आज ही प्योर सिल्विक्रिन आज़माइए.

प्योर सिल्विक्रिन

OBM/1044/Hin M

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

कुछ कड़वी सचाइयां

पंजाब में राष्ट्रपति शासन कायम रखने का एक और फैसला पिछले पखवाड़े किया गया. तीसरी बार यह फैसला किया गया है. और गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम ने संसद को आश्वासन दिया कि 'तमाम शिकस्तों' के बावजूद राज्य का प्रशासन बिलकुल चुस्त है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बिलकुल सक्षम.

यह दावा कितना खोखला है यह इसी बात से उजागर है कि आतंकवादी जब चाहें, जहां चाहें कहर बरपा सकते हैं. लेकिन सरकार है कि हर नृशंस नरसंहार को 'शक्तिहीन होते जा रहे हत्यारों की हताशापूर्ण कार्रवाई' की संज्ञा देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है. सच तो यह है कि हत्याएं भी बढ़ रही हैं और सरकारी भ्रष्टाचार भी. राजीव गांधी ने अपनी पंजाब यात्रा के दौरान इस सच को स्वीकार भी किया है. मगर विडंबना यह है कि इन्हीं सचाइयों को आधार बनाकर बरनाला की निर्वाचित सरकार को बरखास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था.

रेखाचित्र: मंजुला पद्मनाभन

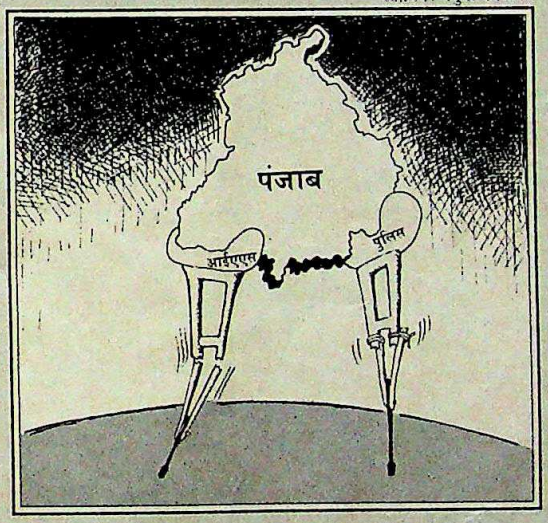

पंजाब आज ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जहां से निकलना दुश्वार लगता है. कोई राजनैतिक समाधान तो शायद ईश्वरीय कृपा से ही संभव हो जैसे. इस राज्य की समस्याएं संकल्प शक्ति की कमी के कारण ही नहीं, दूरदर्शिता के अभाव के कारण भी जटिल हुई हैं. लेकिन पंजाब के धुंधले सामाजिक-राजनैतिक परिदृश्य के पार भी कुछ कड़वी सचाइयां हैं जो स्पष्ट हैं. इन्हें अगर इनके वास्तविक स्वरूप में समझने की कोशिश की गई तो भारत के इस सबसे नाजुक इलाके में ज्यादा शांतिपूर्ण और स्थायी भविष्य की नींव डाली जा सकती है.

हर बर्बर हत्याकांड के बाद यह तथ्य और साफ हो जाता है कि पुलिस का आज का जो स्वरूप है उसके कारण उसे नाकामी ही हाथ लग सकती है. आतंकवादियों की कार्रवाइयों और सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों ने एक अजीबोगरीब तथ्य उजागर किया है. आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य अगर स्थापित राजनैतिक पार्टियों और प्रक्रियाओं को अप्रासंगिक बना देना है तो सरकार के पूरे खेल से भी यही हो रहा है. अब हालत यह है कि एक ओर आतंकवादी हैं तो दूसरी ओर राज्य-व्यवस्था. दोनों के बीच माध्यम के रूप में काम करने के लायक न तो कोई राजनैतिक संस्था है और न कोई प्रशासनिक संस्था.

आतंकवादियों का मकसद हत्याओं से ज्यादा अपनी 'मारक क्षमता' का एहसास कराना होता है. आतंकवाद का विश्लेषण करने वालों का मानना है कि आतंकवादियों की गोली का सबसे उपयुक्त जवाब है व्यापक जन विरोध और भर्त्सना. मगर जब पूरी राजनैतिक व्यवस्था ही अपंग हो गई हो तो यह सब कौन करे. तब तो गोली का जवाब सिर्फ गोली ही रह जाता है.

आज की सबसे बड़ी जरूरत है— जबरदस्त चौकसी और साहसी नेतृत्व. राजनैतिक गतिविधियों के अभाव की कुछ हद तक भरपाई पुलिस और नागरिक प्रशासन कर सकता था. लेकिन दोनों की हालत खस्ता ही है. पंजाब पुलिस पर केंद्र का भरोसा नहीं रह गया है वरना सभी पुलिस प्रमुख— भिंडर, ढिल्लों, रिबेरो, गिल— बाहर से ही लाकर क्यों बिठाए जाते?

राज्य में रिबरो और गिल के 'शीत युद्ध' ने मामले को और पेचीदा ही बनाया है. दोनों के बीच संवाद लगभग बंद हैं. पुलिस अधिकारियों को खेमों में बंटा हुआ मान लिया गया है. इस बीच पुलिस महानिरीक्षक चमनलाल द्वारा लोगों के दमन, और ज्ञात आतंकवादियों के साथ नरमी बरतने की सरकार की नीतियों के विरोध में इस्तीफे ने मामले को और तनावपूर्ण बना दिया है.

उधर नागरिक प्रशासन की हालत भी कोई दुरुस्त नहीं है. डिवीजनल कमिश्नरों और मजिस्ट्रेटों की लगातार शिकायतों से साफ है कि आईएएस और प्रांतीय सेवाओं के अधिकारियों की कुछ नहीं चलती. और तो और, राज्यपाल को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव आर.पी. ओझा का कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा. उनका कार्यकाल बढ़ाने की अभूतपूर्व मांग की गई है.

राज्य के वरिष्ठतम नौकरशाह अरसे से अनिश्चितता की स्थिति में काम करते रहे हैं. कई प्रमुख अधिकारियों का या तो पंजाब के बाहर तबादला कर दिया गया है या किसी गुमनाम-से ओहदे पर भेज दिया गया है. नतीजा यह कि स्थानीय परिस्थितियों और जनमानस की उनकी समझ और उनके अमूल्य अनुभवों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है. बाहर के अधिकारी नया नजरिया तो पेश कर सकते हैं मगर स्थानीय प्रशासकों की सलाह के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते.

पंजाब में आज प्रशासन और जनता के बीच खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि पंजाब के किसान यहां तक मान बैठे कि सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में जानबूझकर भाखड़ा के पानी से बाढ़ ला दी. और, नतीजा यह कि एक योग्य अधिकारी मेजर जनरल बी.एन. कुमार को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी.

विश्वसनीयता का संकट पहले कभी इतना नहीं गहराया था. इसलिए वक्त आ गया है कि सरकार राज्य के जनसंपर्क विभाग वालों की मतलबी प्रेस विज्ञप्तियों के बजाय वक्त की नब्ज को टटोले, दीवारों पर लिखी इबारतों को पढ़े. समस्या का कोई राजनैतिक समाधान नहीं निकल पा रहा है फिर भी सरकार को चाहिए कि वह भिन्न-भिन्न विचारों को सुने और कानूनी व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राज्य में नागरिक और पुलिस प्रशासन के नेतृत्व को विकसित करने के ठोस उपाय करे. वरना खतरा यह है कि पहले से ही हतोत्साहित प्रशासन को कहीं पूरी तरह लकवा न मार जाए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपकी चहेती पत्रिका
आपके दरवाज़े पर
न खरीदने का झंझट...
न खत्म होने का डर

इस सुविधा का लाभ उठाइए.
अपनी चहेती इंडिया टुडे
घर बैठे – नियमित पाइए.
न खरीदने जाने की जरूरत...
न अंक खत्म होने का डर,
इंडिया टुडे
समय से पहुंच जाए आपके घर !

बस कूपन भर कर भेज दीजिए,
देर मत कीजिए !

नाम: _____

डाक पता: _____

मूल्य : वार्षिक रु. 120/-
भुगतान का माध्यम – चैक/मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट

कृपया चैक निम्नलिखित नाम पर बनाएं और इस पते पर भेजें:
तिविंग मीडिया इंडिया लि.
पो. बॉ. नं. 69,
फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

● ऐसी हालत कर दूंगा नेशनल फ्रंट वालों की कि आपको विश्वनाथ को छिपाना मुश्किल हो जाएगा.
■ **बूटा सिंह,** *राजस्थान पत्रिका*

● दरअसल वी.पी. सिंह कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरकर राजनीति कर सकते हैं. देवीलाल और वी.पी. सिंह दोनों ही कुर्सी के बड़े लालची हैं.
■ **हेमवती नंदन बहुगुणा,** *रविवार*

● अगर वी.पी. सिंह शैतान है तो उसे फांसी दे दीजिए. लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि बोफोर्स का पैसा कहां गया.
■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *जनसत्ता*

● उसके (विपक्ष) साथ बातचीत शुरू करना ही मुश्किल है क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि कौन अभी किसी पार्टी में है.
■ **राजीव गांधी,** *दैनिक ट्रिब्यून*

● राजीव गांधी भोलेपन में किसी के विरुद्ध कुछ भी बोल देते हैं और बाद में एक डरपोक नेता के रूप में अपनी गलती मानने में संकोच भी नहीं करते. लेकिन बाद में फिर उसी गलती को दुहराते हैं
■ **रामकृष्ण हेगड़े,** *दैनिक जागरण*

● मुख्यमंत्री से बहस करनी कुश्ती लड़ने जैसा है...वे तब तक कुछ नहीं सुनते जब तक उन्हें धमकी न दी जाए.
■ **गोविंद नारायण सिंह** (*बिहार के राज्यपाल*), प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी में

● हम बहुगुणा को अध्यक्ष के रूप में इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वे विपक्ष को कमजोर करने और उसके एकता प्रयासों को विफल करने के लिए इंका से पैसा लेते हैं.
■ **देवीलाल,** *टेलीग्राफ*

● वे (क्रिकेट टीम के चयनकर्ता) सभी ताश के जोकर हैं.
■ **लाला अमरनाथ** (*मोहिंदर अमरनाथ को टीम में न शामिल किए जाने पर*), *पंजाब केसरी*

● 'नए सिनेमा' के साथ दिक्कत यह है कि यह किसी अभिनेता की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता.
■ **आलोकनाथ,** *टाइम्स ऑफ इंडिया*

● मुझे खुद ही ताज्जुब होता है कि मैं यहां (फिल्मों में) कैसे आ गई, (जबकि) न मैं ग्लैमरस हूं और न मुझे लोगों से मिलने-जुलने का शौक है.
■ **माधुरी दीक्षित,** *आज*

● फिलहाल तो मुझे पता नहीं कि विवाह का क्या मतलब होता है. जिस दिन मुझे लग जाएगा कि इस शब्द का भी कोई मतलब है, इसमें कुछ दम है उस दिन मैं शादी कर लूंगी.
■ **रेखा,** *सिने ब्लिट्ज*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आप बड़ी व्यस्त ज़िन्दगी जीते है जिसका नतीजा होता है मानसिक और शारीरिक थकान, तनाव, पाचन सम्बन्धी समस्यायें और बीमारियों की प्रतिरोधात्मक शक्ति में कमी। इन सबसे जूझने के लिये आपको चाहिये एक खास प्राकृतिक ऊर्जा शक्ति "च्यवनशक्ति" जो 46 से भी अधिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है जिसे खास आपके लिये बनाया है, डाबर ने।

च्यवनशक्ति-दबाव हटाये दिलोदिमाग को ताकत पहुँचाये

स्नायुदबाव से लड़ने के लिये "च्यवनशक्ति" में कई जड़ी-बूटियों का मिश्रण है जैसे- द्राक्षा, अश्वगन्धा, अकरकरा, और गोक्षूर। ये सब पदार्थ शरीर को आराम व स्फूर्ति पहुँचाने का कार्य करते हैं। केसर व दूसरी अन्य जड़ी-बूटियों के मिश्रण से "च्यवनशक्ति" शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के साथ-साथ दिलोदिमाग को ऊर्जा पहुँचाकर उन्हें स्वस्थ रखता है।

अम्लता और पाचन सम्बन्धी समस्याओं से बचाव

अब एसिडिटी (अम्लता) और वायु विकार की गोलियों की जरूरत नहीं है। "च्यवनशक्ति" के प्राकृतिक तत्व जैसे-अकरकरा, लौंग, शहद और मुक्ता शक्ति पिष्टि अम्ल के अधिक बनने को रोकते हैं, पाचनक्रिया को ठीक रखकर भूख बढ़ाते हैं और गैस व आंतों के दर्द में राहत पहुंचाते हैं।

बीमारियों का मुकाबला करने के लिये विटामिन सी से भरपूर

संतरे के रस की अब जरूरत नहीं। च्यवनशक्ति आंवला के गुणों से भरपूर है जो कि विटामिन सी का सर्वोतम स्रोत है। विटामिन सी और इसमें मिश्रित दूसरी जड़ी-बूटियों के कारण च्यवनशक्ति शरीर में साधारण बीमारियों के विरूद्ध स्फूर्तिवर्द्धक प्रतिरोधी शक्ति का संचरण करता है।

यौवन का स्रोत

विटामिन "सी" के साथ-साथ "च्यवनशक्ति" आपको लोहा, कैल्शियम, खनिज, मैग्नीशियम और फास्फोरस आदि प्रदान कर आपके लिये सम्पूर्ण स्वास्थ्य टॉनिक की भूमिका निभाता है।

आप अपने आप को हमेशा युवा महसूस करते हैं और उत्साह आप में हिलोरें लेता है। यह पूर्णतया प्राकृतिक है। अतः आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह हानि-रहित भी है। इसलिये आइये, आज से ही इसे अपनी आदत में शामिल कीजिये।

आप तनाव और दबाव के प्रभाव को छोड़कर और कुछ नहीं खोयेंगे।

खास उनके लिये जो ज्यादा मेहनत करते हैं

नया डाबर च्यवन शक्ति

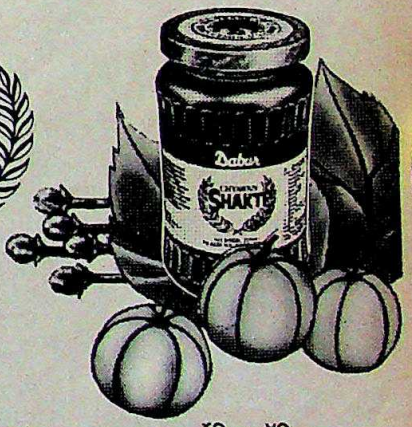

आयुर्वेदिक टॉनिक
आपको हमेशा शक्तिशाली बनाये रखने के लिये।

everest/d88/DIL 371 hin

Bo... Gurukul ...

डाबर इण्डिया लि०
हर्षा भवन, "ई" ब्लाक,
कनाट प्लेस,
नई दिल्ली- 110 001

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जुबां को लगाम

● ताज्जुब है कि ऊधम और बकवास के लिए विख्यात राज्यसभा सदस्य कल्पनाथ राय हाल में बोफोर्स पर संसद में हुई बहस के दौरान न जाने क्यों चुप्पी साधे रहे. इस बहस में बूटा सिंह, कृष्णचंद्र पंत और वसंत साठे सरीखे वरिष्ठ मंत्रियों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को जी भरकर कोसा था.

लगता है बातें बनाने के लिए मणहूर राय को चुप रहने का ही आदेश मिला था. वरना अगर वे बोले होते तो इन मंत्रियों का सारा हो-हल्ला उनके सामने बौना पड़ जाता. एक बार तो वे बोफोर्स के मुद्दे पर जरूरत से कहीं ज्यादा कह गए थे. उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के जन्मदिवस समारोह पर दिल्ली में आमंत्रित किया गया था. वहां मौजूद अनेक मेहमानों के मुताबिक सबसे पहले राय ने शेखी बघारी कि वे उत्तर प्रदेश के उन गिने-चुने साहसी कांग्रेसियों में से हैं जो दावत में आए जबकि दूसरे लोग राज्य में तिवारी-बीरबहादुर प्रतिद्वंद्विता के चलते तिवारी समर्थक ठप्पा लग जाने के डर से दावत में शरीक होने की जुर्रत नहीं जुटा पाए.

इसके बाद बोफोर्स की बारी थी. राय ने अंदेशा जाहिर करते हुए पूछा कि भला प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय हथियार सौदे से 60 करोड़ रु. जुटाने की क्या जरूरत थी जबकि उनके किसी करीबी सहायक के एक टेलीफोन कर देने भर से देशी स्रोतों से ही तुरंत 200 करोड़ रु. तक इकट्ठा हो सकते हैं. इसलिए वफादारी का सबूत पेश कर रहे राय को इस बार चुप रहने का आदेश मिलना ही था.

सब 'जायज' है!

● विपक्षी की टांग खींचने का मौका हो अथवा 'किसी को सबक सिखाने' का, सत्तारूढ दल इंका किसी को भी हथियार बना सकती है चाहे राज्यपाल ही क्यों न हो जिनकी भूमिका गैर-राजनैतिक मानी जाती है. इन माननीय हस्तियों को इशारा कर दिया गया है कि नई दिल्ली के हुक्म का पालन करना ही होगा वरना... इसी इशारे को समझकर केरल की राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा ने महत्वपूर्ण पदो की नियुक्तियों पर अपने दस्तखत मुल्तवी कर रखे हैं. इन नियुक्तियों में विश्वविद्यालय कुलपति सरीखे पद भी शामिल हैं. अब ई.के. नयनार सरकार परेशान है.

उधर आंध्र में राज्यपाल कुमुद बेन जोशी और नंदमूरि तारक रामराव के संबंध रातोरात खट्टे हो गए हैं. कुमुद बेन ने भी रामराव के एक चुनावी वायदे— लोकायुक्त की

कार्टून: मजुला पद्मनाभन

नियुक्ति—को मंजूरी देने में देरी कर दी है. इस पद के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एन. अग्रवाल का चयन हो गया है लेकिन कुमुद बेन के मेहरबान होने तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा. इंका ने खुलेआम यह दिखा दिया है कि वह विपक्षी सरकारों वाले राज्य में भी अपनी चला सकती है.

उनको भी दिया

● भारत में एक साल चले, और मिखलाइल गोर्बाचेव की यात्रा के साथ खत्म होने वाले सोवियत महोत्सव ने दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को भले ही मजबूत किया हो पर अनेक रूसी कलाकारों का इस देश के बारे में काफी कटु अनुभव रहा है.

ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका की

भावना के रंग में रंगे ये कलाकार यहां तक कहते सुने गए कि भारतीय नौकरशाह तो दौरों का इंतजाम करने जैसे मामलों में भी हद दर्जे के लालफीताशाह हैं. लेकिन भारत की महंगाई से पाला पड़ने पर उन्हें सचमुच ही धक्का पहुंचा.

हर कलाकार के रहने की व्यवस्था होटल में किए जाने के अलावा उसे खाने के लिए 200 रु. रोज दिए जाते थे. किसी अच्छी खुराक वाले शख्स के लिए यह पैसा बिलकुल नाकाफी था. दो लोगों के बढ़िया रात्रिभोज के साथ पारंपरिक वोदका के लिए तो यह कतई पर्याप्त न था. प्रति व्यक्ति इतने कम भत्ते की बात ज्यों ही रूस में फैली, कलाकारों के दल अपने साथ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ लाने लगे.

और जिन लोगों ने खाने के मामले में हाथ खींचकर खर्च किया उन्होंने मौज-मस्ती और खरीद-फरोख्त के लिए थोड़ा पैसा बचा लिया. वे आखिरी दिनों में जैकेट, चमड़े के वस्त्र, जेबी कैलकुलेटर, क्वार्ट्ज घड़ियां, वॉकमैन और पश्चिमी पॉप संगीत के कैसेट सरीखी विलासिता की सामग्री खरीदते देखे गए. ये चीजें उनके यहां दुर्लभ हैं. आखिर इस विकासशील देश में भी विकसित देशों को देने के लिए कुछ तो है.

लाजवाब दूतावास

● वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा सिख अलगाववादी गुटों के भारत विरोधी प्रचार का मुंहतोड जवाब न दे पाने की वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी उससे नाराजगी जाहिर करते आए हैं.

इन गुटों का असर इस कदर बढ़ गया है कि हाल ही के हफ्तों में ये अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पंजाब के सिखों का मसला उठवाने में कामयाब रहे हैं. निचले सदन में पारित एक प्रस्ताव में यहां तक मांग की गई कि सिखों को भारत सरकार के उत्पीड़न से बचाया जाए.

लेकिन इंडियाना के डॉन बर्टन द्वारा निचले सदन में दिए गए उत्तेजक भाषण से तो विदेश मंत्रालय सकते में आ गया. बर्टन का कहना था कि "प्रधानमंत्री राजीव गांधी को होश में आकर सिखों को आजादी दे देनी चाहिए."

अब विदेश मंत्रालय यह जानना चाहता है कि वाशिंगटन स्थित खालिस्तान परिषद सरीखा आधारहीन गुट कैसे अमेरिकी संसद को प्रभावित कर पाया और वहां अपनी बात भी रखवा दी, जबकि सारे साधनों के बावजूद भारतीय दूतावास अपना दृष्टिकोण मनवाने में नाकाम रहा. पर दूतावास के पास इसका कोई जवाब नहीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विस्फोटक डिब्बे

■ अगर दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि किसी विमान, विमानाघर या किसी भवन में बम रखे जाने की खबर पुलिस को मिली और घंटों लंबी तलाशी के बाद इसे कुछ भी हाथ नहीं

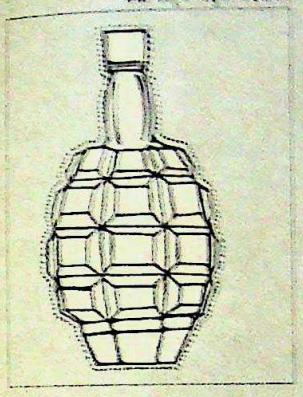

लगा. मगर ऐसे हर मामले में पुलिस के हाथ सिर्फ नाकामी ही लगे, भला यह कैसे हो सकता है? पिछले दिनों ऐसी ही एक कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के हाथ जो माल लगा वह किसी बम की तरह विस्फोटक भले ही न हो पर इसके पीछे छिपा शोर किसी डायनामाइट से कम नहीं था.

एक सूबह पुलिस कंट्रोल रूम को किसी ने फोन पर खबर दी कि दिल्ली से बंबई जाने वाली राजधानी ट्रेन में बम रख दिया गया है. खबर मिलते ही कंट्रोल रूम के सभी संबंधित अधिकारियों और चौकियों को सतर्क कर दिया. साधारण बताया हुआ पुलिस का बम दस्ता स्टेशन पर पहुंचा लेकिन इससे पहले ही रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी. रेलवे अधिकारियों को तुरंत सिग्नल दिया गया और गाड़ी को तुगलकाबाद स्टेशन पर रोक लिया गया. पुलिस ने हर डिब्बे और हर यात्री की जांच की और आखिर गत्ते के ऐसे तीन डिब्बे ढूंढ निकाले गए जिनका कोई वारिस नहीं था. बम निरोधक दस्ते ने जब सावधानी से उन्हें खोला तो बम तो नहीं फटा पर खोलने वालों की आंखें जरूर फटी की फटी रह गईं. डिब्बों में विदेशी शराब की बोतलें भरी हुई थीं जिन्हें पुलिस ने नियम के अनुसार ठीक जगह जमा करवा दिया.

'क्लेमेंट्स' चोर

■ चिकित्साशास्त्र के इस जमाने के हुनरमंदों का आलम यह है कि आक-नाक-आंख के डॉक्टर भी दाएं और बाएं काम की डाक्टरियों के आधार पर अपनी-अपनी अलग बिरादरियां बनाने लगे हैं. और खास बात यह है कि चिकित्साशास्त्र के इन नए नवाब चोरों को बिरादरी में भी यहूदी बड़े जतन से जगह है. कम-से-कम दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो चोरों की बिरादरी अलग-अलग महारतों में बंट गई है. महारतों की इस सूची में पिछले दिनों एक और महारत शामिल हो गई—क्लेमेंट्स की चोरी.

पिछले पखवाड़े दक्षिण दिल्ली के एक थाने में चोरी की शिकायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह कई दिन तक चलता रहा. इन शिकायतों की एक साझी खूबी तो यह थी कि रपट लिखाने वाले लगभग सभी लोग डॉक्टर, वकील और आर्किटेक्ट जैसे धंधों के लोग थे और दूसरी यह कि सब लोगों की एक ही शिकायत थी कि कोई चोर उनके साइनबोर्ड और नेमप्लेट ले उड़ा है और चोर शहर की दीवारों तक के उनके पहचानों से अपने सूचनापटों और बल्बों को मुक्त नहीं—शायद इस कारण कि वे कोई किसी दूसरे चोर के अधिकार क्षेत्र में न आते हैं.

शिकायतों की भरमार से तंग

आकर आखिर जब पुलिस ने मामले की पड़ताल के लिए दौड़-धूप की तो चोरी का सारा माल एक स्थानीय कबाड़ी के यहां मिल गया जो 25 रुपए किलो के भाव से यह माल बेच रहा था.

नकल की ट्रेनिंग

■ परीक्षाओं में नकल का चलन देखते हुए शिक्षा विभाग अब यह मानकर बैठ चुका है कि इस समस्या से दो-चार साल में पार नहीं पाया जा सकता. इसलिए ऐसा कोई विश्वविद्यालय या बोर्ड

नहीं जिसने नकल विरोधी उड़न-दस्तों का स्थायी तौर पर गठन न कर लिया हो. इन दस्तों का लक्ष्य यही है कि नकलचियों के दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हौसले और उनकी तरकीबों का जमकर मुकाबला किया जाए. इस सरकारी मोर्चेबंदी के सामने बेचारे नकलचियों की रक्षा के लिए अक्सर कई लोग परीक्षा के दिनों में किताबों, पर्चियों, लाउडस्पीकरों और चाकू-छुरों से लैस होकर मैदान में कूदते रहते हैं. पर ताजा समाचारों से यह लगता है कि नकलचियों की रक्षा का यह 'परोपकारी' काम अब एक व्यवसाय का रूप लेने जा रहा है.

पिछले कुछ दिनों से कलकत्ता की उपनगरीय रेलगाड़ियों में चलने वाले यात्रियों को ऐसे पर्चे पढ़ने को मिल रहे हैं जिनमें 'टूकली' (नकल) करने का प्रशिक्षण देने वाले एक स्कूल का विज्ञापन छपा है. यह विज्ञापन खास तौर से उन विद्यार्थियों के नाम जारी किया गया है "जिनकी रुचि पढ़ने में नहीं बल्कि सिर्फ पास होने" में है. केवल सात दिनों का 'क्रैश कोर्स' देने वाले इस 'टूकली ट्यूटोरियल होम' की खासियत बयान करते हुए दावा किया गया है कि यहां 'आधुनिक और वैज्ञानिक' तरीके से नकल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है.

चोर रंगे मुंह गिरफ्तार

■ आम तौर पर होता यह है कि चोर चोरी करके गायब हो जाता है और पुलिस केवल जांच-पड़ताल करके और शिकायत करने वाले के यहां बर्फी-समोसों पर हाथ साफ करके अपना फर्ज पूरा कर लेती है. ऐसा बहुत विरले ही होता है कि चोर को पकड़ लिया जाए—और यह तो लगभग नामुमकिन ही है कि चोर को हाथोहाथ पकड़ भी लिया जाए और उसे हवालात में भी बंद कर दिया जाए. लेकिन ऐसा ही एक नामुमकिन काम पिछले दिनों हावड़ा जिले के श्यामपुर थाने की पुलिस ने कर दिखाया और चोर को रंगे मुंह गिरफ्तार करके हथियारबंद गारद की देखरेख में हवालात में डाल दिया.

हुआ यह कि एक गांव में रात के समय मुर्गियों के बाड़े में हंगामा उठ खड़ा हुआ तो गांव भर के लोग मुर्गी-चोर को पकड़ने के लिए लाठियों समेत बाड़े के इर्दगिर्द आ जमा हुए. टार्चों और लालटेनों की रोशनी में जब चोर की तलाश हुई तो लोग यह देखकर दंग रह गए कि यह कोई छोटा-मोटा उचक्का नहीं बल्कि चीते का लगभग पौने चार फुट लंबा बच्चा था जो शिकार की तलाश में जंगल से मुर्गीखाने में आ घुसा था और कोने में आराम से मुर्गी का नाश्ता कर रहा था. खबर मिलने पर स्थानीय

थाने से पुलिस की गारद आ पहुंची. 'चोर' को पकड़ कर थाने ले जाया गया और हवालात में बंद कर दिया गया. बाद में कलकत्ता चिड़ियाघर के लोग उसे ले गए.

—संकलन: विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

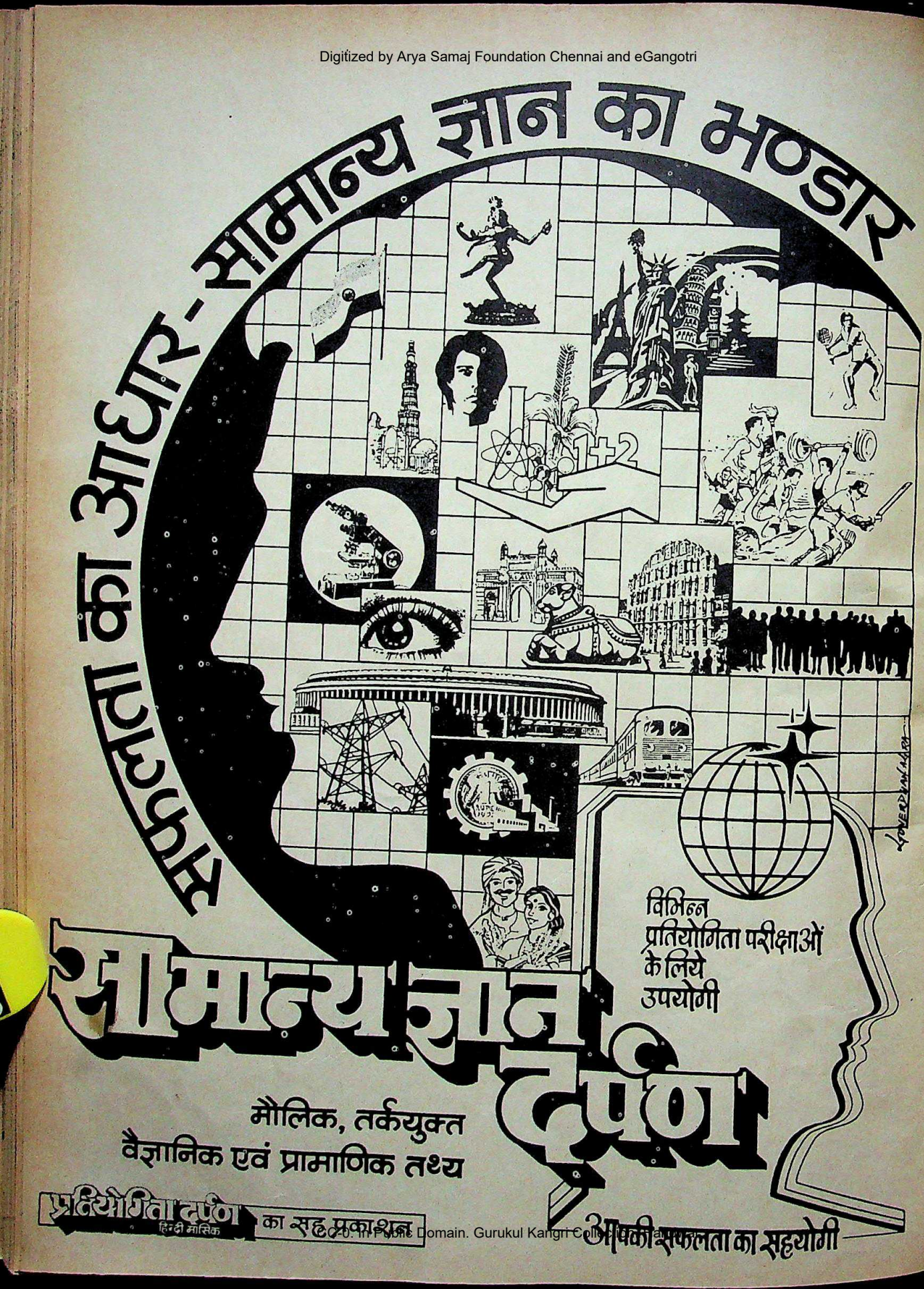

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेरे प्यारे भारत,

पिछले 15 दिनों में देश में इतनी सारी घटनाएं घट गईं कि मुझे लगा कि तुम्हें पत्र लिखना चाहिए. मगर दिलचस्प बात तो यह है कि पत्र लिख लेने के बाद मुझे लगा कि इन तमाम घटनाओं के बारे में शायद तुम पहले भी सुन चुके होगे.

मुझे याद आ रहा है कि बोफोर्स मामले का जिक्र पहले भी मैं कर चुका हूं. हां, वही स्वीडिश होवित्जर तोप! और यह भी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी एक शख्स हैं जो राह चलते आरोप उछाला करते हैं. इस बार उन्होंने एक बड़ा धमाका किया है. नहीं, नहीं, बम का नहीं!

भवान सिंह

विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे शख्स हैं जो राह चलते आरोप उछाला करते हैं. इस बार उन्होंने एक बड़ा धमाका किया

वास्तव में इस बार आरोप काफी गंभीर है और सीधे-सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर लगाया गया है. विश्वनाथ ने कुछ पुराने दस्तावेज पेश किए और दावा किया कि स्विस बैंक में 'लोटस' नाम से जो खाता है वह राजीव का ही है और दलाली का पैसा उसी में जमा कराया गया. तर्क यह कि लोटस यानी कमल और राजीव समानार्थक शब्द हैं.

पिछली बार जब बोफोर्स का मामला संसद में पेश किया गया था तब जो हंगामा हुआ था उसकी याद होगी ही. इस बार सत्तादल ने संसद में मामला विश्वनाथ के खिलाफ कर दिया. उन पर आरोप लगाया गया कि स्विस बैंक में यूनिवर्सल ट्रेडर्स नाम से जो खाता है वह विश्वनाथ का ही है. तर्क यह दिया गया कि यूनिवर्स का मतलब विश्व होता है. बेचारे स्विस बैंक वाले! उन्हें भी भारतीय खातों के बारे में संस्कृत की शिक्षा लेनी पड़ी होगी.

बहरहाल, एक मोर्चे पर धमाका करने के बाद विश्वनाथ दूसरे मोर्चे को संभालने में लग गए. तुम्हें याद होगा, यह मोर्चा विपक्षी मोर्चे के नाम से जाना जाता है. इसकी हालत अभी भी जस की तस ही है. इसके एक घटक लोकदल में फूट पड़ रही है, तो नेता हेमवती नंदन बहुगुणा का निष्कासन हो रहा है. और बहुगुणा की हालत यह है कि वे दावा तो करते हैं कि विपक्ष में हैं मगर उनका आचरण सत्ता पक्ष के किसी सदस्य जैसा है.

गोर्बाचेव राजीव को भरोसा दिलाने भारत आए कि भारत-रूस मैत्री बिलकुल दुरुस्त है

प्रमोद पुष्करणा

और तुम महान भारत-रूस सांस्कृतिक समागम को भूले नहीं होगे. उन समारोहों के समापन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव खुद दिल्ली आए और राजीव को भरोसा दिलाया कि भारत-रूस मैत्री बिलकुल दुरुस्त है और चीन की छाया उस पर नहीं पड़ेगी. गोर्बाचेव की इस यात्रा का नतीजा यह रहा कि दोनों देशों के संबंध और गहरे हुए.

तुम्हें ऊब तो होगी मगर यह लिखना ही पड़ेगा कि कुछ और ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में तुम पहले भी सुन चुके होगे. आतंकवादियों ने एक और नरसंहार किया और सरकार ने फिर कहा कि सब कुछ काबू में है. इंडियन एअर-लाइंस की हड़ताल ने हजारों विमानयात्रियों को परेशान कर दिया. राजीव अमेठी गए और उन्होंने घोषणा की कि वे अगला चुनाव फिर वहीं से लड़ेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मध्यावधि चुनाव नहीं होने वाला. लेकिन उनकी साख जिस तरह घटी है उसके कारण लोग तो क्या उनकी अपनी पार्टी वाले भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं.

और अंत में एक नई खबर. दलबदल पर रोक के कानून की याद तो है न? अब पहली बार एक संसद सदस्य की सदस्यता इस कानून के तहत समाप्त कर दी गई है, क्योंकि कांग्रेसी टिकट से जीतने के बाद वह विपक्षी खेमे में चला गया. यह सदस्य सुदूर उत्तर-पूर्व का भले हो मगर उसकी बर्खास्तगी के दिलचस्प नतीजे हो सकते हैं. संभव है विश्वनाथ प्रताप सिंह अगले शिकार हों. तब क्या होगा इसकी कल्पना भर ही की जा सकती है.

तुम्हारा वही
दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

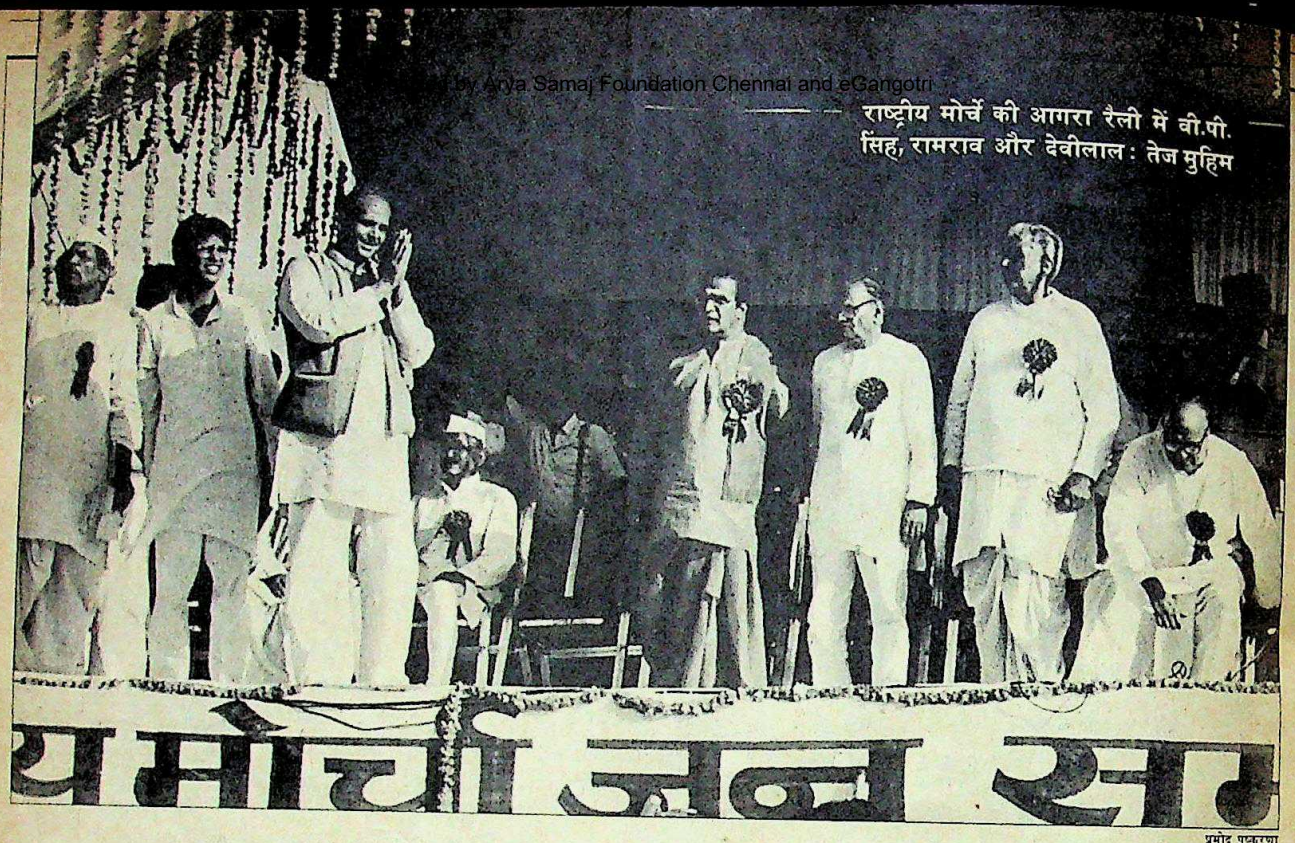

राष्ट्रीय मोर्चे की आगरा रैली में वी.पी. सिंह, रामराव और देवीलाल : तेज मुहिम

प्रमोद पुष्करणा

राजनैतिक माहौल

ओछा अभियान, घटिया जुमले

लड़ने-झगड़ने का उनका अंदाज वैसा ही लगता है जैसा गली-कूचों के बदमिजाज, फालतू लोगों का होता है. और उनकी भाषा भी लगभग वही है. हां, जिक्र कांग्रेस और विपक्ष का ही है. आगामी चुनाव के पहले ही जिस तरह वे आपस में तू-तू, मैं-मैं कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि 1989 के आम चुनाव में प्रचार का स्तर किन निचाइयों को छूने वाला है.

देश में लोकतांत्रिक बहस का स्तर कितना नीचे गिर सकता है यह पिछले पखवाड़े जाहिर हो गया. आजादी के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का विषवमन और इस तरह की क्षुद्रता पहले नहीं देखी गई थी. केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री या संसद सदस्य या फिर विपक्ष के नेता—हर किसी की जुबान जैसे गंदी हो गई है. इस पूरी अवधि के दौरान जिस तरह की कीचड़ उछाल हुई, उससे तो जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के चेहरे ही काले हो गए. और इस पागलपन में व्यक्तिगत द्वेष की बलिवेदी पर कुरबान कर दी गई मुद्दे पर आधारित राजनीति. नालों की गंदगी जैसे संसद के भीतर पहुंच गई जहां कांग्रेसी सांसद अपने विपक्षियों को देशद्रोही, परजीवी, झूठा, पागल तक कहने से नहीं हिचके. और विपक्ष भी जैसे को तैसा देने की मुद्रा में दिखा. आगरा में राष्ट्रीय मोर्चे की एक खासी बड़ी सभा में उनके तेवर सत्ता दल के किसी सम्मानजनक विकल्प के बजाय गली-कूचों के लड़ाकों जैसे ही दिखे.

सारे विवाद की जड़ था—बोफोर्स का मुद्दा. आम चुनाव की संभावनाओं के मद्देनजर विपक्ष एक बार फिर बोफोर्स के प्रेत को जगाने में लग गया. उधर सत्ता दल भी विपक्ष की इस कोशिश को नाकाम करने की पुरजोर तैयारी में था. पिछले हफ्ते 'द हिंदू' ने फिर जैसे बोरीभर दस्तावेज प्रकाशित कर दिए. उनसे यह तथ्य और भी पुख्ता होता है कि बोफोर्स कंपनी ने अपनी तोपों के सौदे को पटाने के लिए भारतीयों को करोड़ों रुपए की दलाली दी. यह रहस्योद्घाटन राजीव गांधी के लिए एक और करारा झटका था, क्योंकि वे कई बार यह बयान दे चुके हैं कि इस सौदे में "किसी भारतीय ने कोई पैसा नहीं लिया या यह कि भुगतान 'करार समेटने' या 'औद्योगिक खुफियागीरी' के लिए किया गया."

लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के कट्टर शत्रु—विश्वनाथ प्रताप सिंह—ने जिस ढुलमुल तरीके से इस मुद्दे को उठाया, उससे लगता है कि ये नए सबूत भी ज्यादा असरकारक नहीं होंगे. दुर्भाग्य से संसद में इस मामले पर गाली-गलौज और विषवमन का जो दौर चला उसमें असली मुद्दा दबकर रह गया. पहले ही दौर में विपक्ष की हार का श्रेय किसी और को नहीं, बल्कि खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह को ही जाता है.

अब से पहले जब भी प्रधानमंत्री अथवा सत्ता दल पर सीधा हमला करने का मौका होता तो वे तमाम तरह की सावधानियां

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमेठी

हौसला अफजाई

नेताओं में भी प्रवासी परिंदों का गुण होता है. हर बार चुनावी मौसम आते ही वे अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में फेरी लगाने लगते हैं. पिछले पखवाड़े प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अपने क्षेत्र की जनता से मिलने रायबरेली और अमेठी पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे. इससे इस संभावना को ही बल मिला कि प्रधानमंत्री जल्दी ही आम चुनाव कराने पर विचार कर रहे हैं.

उनका मकसद एकदम साफ था और वह यह कि जहां तक संभव हो जनता से नजदीकी संवाद कायम करना और औपचारिकता के घेरे से निकलकर अनौपचारिक नजर आना. गौरीगंज के 41 वर्षीय पान विक्रेता श्रीराम कहते हैं, "इस बार ही लोगों को मौका मिला कि जिसे उन्होंने वोट दिया था, उसे नजदीक से देख सकें." हर कहीं ऐसा ही आलम था. अपने चुनाव क्षेत्र के 250 किलोमीटर रास्ते को तय करते हुए प्रधानमंत्री ने आखिर अपना सुरक्षा कवच तोड़ ही डाला और हर साल होने वाले 'कार्तिक पूर्णिमा मेले' में भी भाग लिया. मेले में घूमने से पहले बाबा नंदमेहर के मंदिर में जाकर पूजा की. यह बात दीगर है कि बहुत से लोगों पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ा. दूरदराज के इलाकों से पूजा करने आए और भूत-प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए फकीरों की तरह नाचते लोगों को राजीव के आने के घंटों पहले सुरक्षा जवानों ने बाहर खदेड़ दिया था. पूजा-अर्चना करने आए एक लाख से ज्यादा लोगों को पटाने के लिए राजीव के हाथ अच्छा मौका लगा था. घूमते वक्त उन्होंने गरमागरम जलेबियां चखीं.

सितंबर में चार बार टले राजीव के इस दौरे ने लोगों में खासी रुचि जगा दी थी. अखबार भी लिखने लगे थे कि इस चुनाव क्षेत्र में जनमोर्चा नेता संजय सिंह की तेजतर्रार गतिविधियों की वजह से प्रधानमंत्री भयभीत हो गए हैं. संजय ने यह घोषणा भी की थी कि वे राजीव को अमेठी में नहीं घुसने देंगे. लेकिन ज्यों ही संजय ने अमेठी से नई दिल्ली की अपनी 'पदयात्रा' का एलान किया, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर को हुई, तत्काल ही राजीव के दौरे की घोषणा भी कर दी गई.

पर शुरू में हवा का रुख सत्तारूढ़ दल के अनुकूल नहीं था. 22 नवंबर को रायबरेली में हुई उनकी पहली आमसभा में महज 35,000 लोग आए और राजीव के 'जय हिंद' कहने से पहले ही इसमें से आधे रुखसत हो चुके थे. राजीव ने उसी दिन और आगे भी बार-बार जोर दिया कि वे निश्चित रूप से 'अमेठी और केवल अमेठी' से ही चुनाव लड़ेंगे.

अगले दिन अमेठी दौरा सुबह 8.30 बजे शुरू हुआ. आधी रात तक चले इस दौरे के नतीजे काफी उत्साहजनक रहे. सभाओं में भारी भीड़ रही.

इस दौरे से संबंधित लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ा. खासकर संजय सिंह की मुहिम के बाद से स्थानीय इंका कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया था. आम तौर पर मीठा बोलने वाले नारायणदत्त तिवारी के उग्र भाषण ने तो केंद्रीय संचारमंत्री बीरबहादुर सिंह के कटु वचनों को भी फीका कर दिया.

—दिलीप अवस्थी, अमेठी में

अमेठी में राजीव और सोनिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बरतते, वक्रोक्तियों का सहारा लेते. लेकिन 4 नवंबर को पटना में दिए अपने भाषण में विश्वनाथ ने दावे से कहा कि दरअसल बोफोर्स कंपनी ने जिस स्विस खाते में रकम जमा कराई वह राजीव गांधी का ही था. और यहां वे भारी रणनीतिक भूल कर बैठे. यह बयान देकर उन्होंने इंका को उन पर हमला करने का वह हथियार थमा दिया जिसकी उसे अरसे से तलाश थी. कांग्रेसी सांसदों ने विश्वनाथ को चुनौती दी कि उनमें हिम्मत हो तो यही आरोप वे सदन में दोहराएं. जवाब में विश्वनाथ जब झिझके और हकलाए तो बस उनके ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा.

वाक्युद्ध इतना तीखा हुआ कि शालीनता को तिलांजलि दे दी गई. गृहमंत्री बूटा सिंह के अधिकांश भाषण को लोकसभा के रिकार्ड से निकालना पड़ा. माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी ने तो एक मौके पर के.के. तिवारी के भाषण को "कुल मिलाकर अश्लील और निरर्थक" बताया. लेकिन कुछ ही मिनट बाद वे खुद भी उसी स्तर पर उतर आए जब उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा, "उन्होंने वी.पी. सिंह पर विपक्ष के हमबिस्तर होने का आरोप लगाया है. उम्मीद है वे कांग्रेसियों के हमबिस्तर नहीं बनेंगे, वरना उन्हें एड्स हो जाएगा." यही नहीं, विश्वनाथ की पत्नी, मां, पिता, बच्चों और बाकी रिश्तेदारों के नाम भी इस बहस में घसीटे गए. कांग्रेस (स) के नेता के.पी. उन्नीकृष्णन कहते हैं, "मैंने संसद में 18 साल बिताए हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा." जनता दल के नेता जॉर्ज फर्नांडीस की टिप्पणी थी, "इसे मछली बाजार कहना भी उस बाजार की बेइज्जती ही होगी."

हालांकि इस बहस की शुरुआत जनता दल के मधु दंडवते ने की थी, लेकिन उन्हें अपने इस मुद्दे को सही तरीके से पेश करने का भी मौका नहीं दिया गया कि सरकार के बार-बार इनकार करने के बावजूद अब यह साबित हो चुका है कि 1700 करोड़ रु. के तोप सौदे में दलाली दी गई है.

लेकिन इंकाई सदस्य होहल्ला करके असली मुद्दे के बजाय सारा ध्यान विश्वनाथ के पटना वाले बयान पर केंद्रित करने में लगे रहे. दलाली का पैसा किसकी जेब में गया, यह मामला भुला दिया गया. दंडवते कहते हैं, "सत्ता दल की पूरी कोशिश यह थी कि मेरी बहस के इस असली मुद्दे से ध्यान हटा दिया जाए कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ने संसद में झूठ बोला. लेकिन अपना बचाव करने में वे इतना गिर जाएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री ने ससद के विशेषाधिकारों का हनन किया है."

बहस का रुख पलटने में सत्ता दल ने अभूतपूर्व एकजुटता का प्रदर्शन किया. बूटा सिंह और वसंत साठे समेत पांच मंत्री और दो महासचिव इस बहस को विश्वनाथ विरोधी प्रचार बनाने में जी-जान से जुट गए. विदेश राज्यमंत्री के.के. तिवारी ने विश्वनाथ को चुनौती दी कि वे दलाली के सबूत वाले दस्तावेजों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उन पर दस्तखत करें. जब विश्वनाथ उन दस्तावेजों पर दस्तखत करने लगे तो बूटा सिंह और गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम ने एक नई मांग पेश कर दी कि वे पटना वाले अपने भाषण की खबरों को भी प्रामाणिक साबित करें, यानी वे लिखित में दें कि संबंधित स्विस खाता राजीव का है.

इसके बाद इंका ने इस आशय के पोस्टर छपवाए कि 'विश्वनाथ का झूठ पकड़ा गया'. ये पोस्टर देश भर में दीवारों पर चिपकाए गए. जाहिर है, इंका राजीव के एकमात्र सशक्त प्रतिद्वंद्वी द्वारा दी गई चुनौती को बड़ी गंभीरता से ले रही है. विश्वनाथ को 'ध्वस्त' करने की मुहिम में तेजी लाने का फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक उच्चस्तरीय मंत्रणा के बाद किया गया है. इस मुहिम में सत्ता दल का सबसे विश्वस्त सहयोगी दूरदर्शन भी शरीक दिखा. उसने टीवी पर वह बैनर भी दिखाया जिस पर लिखा था 'वी.पी. सिंह अपने आरोप साबित करने में असफल रहे.' इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसदों द्वारा विश्वनाथ के खिलाफ दिए गए भाषणों के अंश भी शामिल किए गए. विश्वनाथ को जवाब देने का वक्त भी नहीं दिया गया. और इस कार्यक्रम को एक हफ्ते में एक नहीं तीन बार दिखाया गया.

टीवी के परदे पर चले इस प्रचार को सहारा दिया पार्टी मशीनरी ने जिसे हाल ही में सक्रिय किया गया है. सभी प्रदेश इंका अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया और हिदायतें दी गईं कि विश्वनाथ के खिलाफ मुहिम कैसे चलानी है. प्रदेश इंका अध्यक्षों से कहा गया कि वे राज्यों की राजधानियों में हफ्ते भर के अंदर बैठक करें और विश्वनाथ विरोधी मुहिम की रणनीति तय करें. महासचिव गुलाम नबी आजाद का कहना है, "अब हम श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिखा देंगे कि झूठ के सहारे राजनीति में टिके रहना कितना मुश्किल होता है. वे जल्द ही राष्ट्रीय राजनैतिक मंच से गायब नजर आएंगे." भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुकुल वासनिक का कहना था, "अब वक्त आ गया है कि वी.पी. सिंह को उनकी औकात बता दी जानी चाहिए. उनके पास

बूटा सिंह, वसंत साठे समेत पांच मंत्री और दो महासचिव संसदीय बहस को विश्वनाथ विरोधी मुहिम बनाने में जुट गए. इस वाक्युद्ध में शालीनता को तिलांजलि दे दी गई. बूटा के तो अधिकांश भाषण को रिकार्ड से हटाना पड़ा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय झूठ के पुलिंदे के."

बहरहाल, विश्वनाथ अखबारों और पत्रिकाओं में छाये रहे हैं. विपक्षी नेता भी कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत विश्वनाथ को दरकिनार करने के बजाय उनका ज्यादा जोरदार तरीके से समर्थन करते नजर आए, मानो वे ही देश के एकमात्र विश्वसनीय नेता हों. लोकदल के महासचिव शरद यादव का कहना है, "जाहिर है, इंका को विश्वनाथ का प्रेत सताता रहता है. लगता है प्रधानमंत्री की रातें करवटें बदलते ही गुजरती हैं. उन्होंने अब जाकर महसूस किया है कि विश्वनाथ को भ्रष्ट प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया गया है." जनता दल ने भी तुरतफुरत बोफोर्स मसले का इस्तेमाल अपने प्रचार अभियान में शुरू कर दिया. मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके का दौरा कर रहे फर्नांडीस के मुताबिक "बोफोर्स ही छाया रहा."

अलग-थलग पड़ जाने के डर से विश्वनाथ और भी आक्रामक नजर आए. उनके एक सहयोगी ने कबूल किया, "उन्हें यह अहसास हो गया कि इंका की चुनौती का सीधे-सीधे मुकाबला करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो खत्म हो सकते हैं." खुद विश्वनाथ का कहना है, "बोफोर्स मामले पर दिए गए अपने बयान के हर शब्द पर मैं कायम हूं. यदि मैं भ्रष्ट अथवा पागल हूं तो मुझे आप फांसी पर लटका सकते हैं. लेकिन बोफोर्स की दलाली आखिर कहां गई? राजीव गांधी मुद्दे को दरकिनार करके देश को मूर्ख नहीं बना सकते."

बहरहाल, विपक्ष भी देश के कुछ हिस्सों में अपनी मुहिम छेड़ने और सत्ता दल के आक्रमण के मुकाबले के लिए अपनी घटिया चालों को इस्तेमाल करने की तैयारी में है. अब एक बात तो तय है कि विश्वनाथ दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर मुहिम छेड़ने वाले हैं जिसमें भ्रष्टाचार और राजीव गांधी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा. और लगता है कि इस बार सचाई को राह का रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा.

अगले लोकसभा चुनावों के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे यह साफ होता जा रहा है कि अब तक का सबसे गंदा चुनाव प्रचार अभियान बस शुरू ही होने वाला है. इसमें पार्टियां किसी भी स्तर तक नीचे गिरने को आमादा हैं. जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में यह कैसी श्रद्धांजलि है!

—प्रभु चावला, डेविड देवदास और इंद्रजीत बधवार

जन्मशती समारोह

तेरे मेरे किसके नेहरू?

वे जवाहरलाल नेहरू की क्या गत बना रहे हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता को उन्होंने इंका के प्रचार का मोहरा बना दिया है. नेहरू डाक टिकट, नेहरू सिक्के, नेहरू बैज, उनके भाषणों के कैसेट, नेहरू डायरी, नेहरू कैलेंडर सब कुछ चल पड़ा है. और तो और देश भर में नेहरू साहित्य की विमान वर्षा करने की भी योजना है.

नेहरू जन्मशती समारोह पिछले पखवाड़े तीन मूर्ति भवन में शुरू हुए. लता मंगेशकर ने स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों के सामने खड़े होकर गीत गाए. दिल्ली की दीवारों, सड़कों पर नेहरू के चित्रवाले पोस्टर रातोरात चिपका दिए गए. सरकारी प्रोत्साहन के बूते एक पूरा का पूरा 'नेहरू उद्योग' ही चल पड़ा है. इसके तहत सिर्फ श्याम बेनेगल का 52 प्रकरणों वाला 'भारत: एक खोज' धारावाहिक ही नहीं बना बल्कि मंजू सिंह के छह भागों वाला 'पीपुल रिमेंबर' व दूसरे कार्यक्रम भी बने.

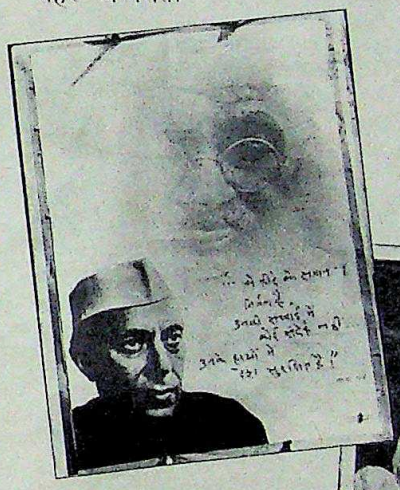

विपक्ष खुले तौर पर और कई कांग्रेसी निजी तौर पर मानते हैं कि इस पूरे तामझाम में नेहरू वाली भावना नदारद है. कई साल तक कांग्रेस (एस) में रहकर फिर इंका में लौट आने वाले पुराने कांग्रेसी ए.जी. कुलकर्णी कहते हैं. "मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए तो यह महज अमेरिकी शैली का दिखावटीपन ही है." भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, "यह आयोजन तो परिवारवाद कायम करने की कसरत ही है. करतबबाजी तो एक बात है पर सत्ता दल की राजनीति पर जनता का पैसा खर्च करना निहायत गलत है."

जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मधु दंडवते की शिकायत है कि दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मशती को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी जा रही है. वे कहते हैं, "वे इसी उत्साह से आचार्य नरेंद्र देव की जन्मशती क्यों नहीं मनाते? क्या सिर्फ इसलिए कि वे समाजवादी दल के थे?"

सत्ता दल के लोग इस बात से इनकार करते हैं कि वे नेहरू और उनकी विरासत का फायदा उठा रहे हैं. इंका के लोकसभा सदस्य और कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद कहते हैं, "नेहरू जन्मशती समारोह समिति में विपक्षी सदस्य भी हैं. हम नेहरू को बेच नहीं रहे. उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है."

हाल ही में नेहरू पर किताब लिखने वाले 'टेलीग्राफ' के संपादक एम.जे. अकबर को डर है कि नेहरू को जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है, उसके कारण उनकी छवि "महज रुमानी बनकर ही न रह जाए." वामपंथी खेमे के इतिहासकार बिपिन चंद्रा मानते हैं कि "नेहरू प्रचार के मोहताज नहीं." उनके अनुसार तो यह विपक्ष ही है जिसने "नेहरू जन्मशती मनाने का जिम्मा शासक दल को सौंपा था." पर असली सवाल अभी भी जस का तस है—नेहरू किसके हैं?

—मधु जैन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: प्रमोद पुष्करणा

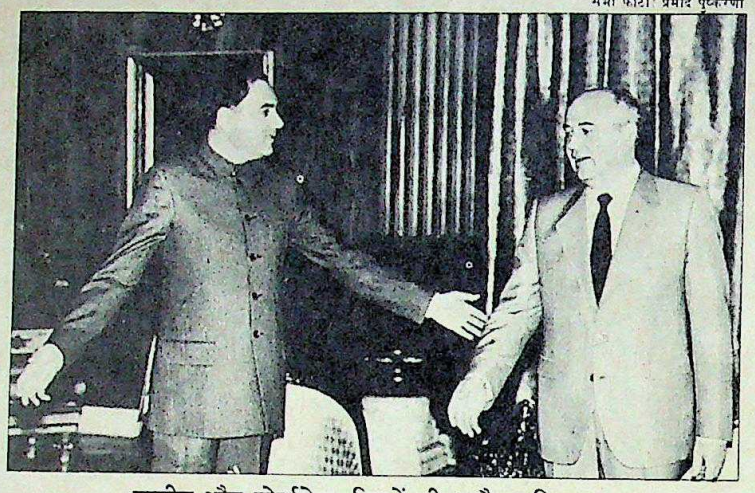

राजीव और गोर्बाचेव: रिश्तों की अनौपचारिकता

भारत-रूस संबंध

बदलाव की प्रक्रिया

पिछले पखवाड़े सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की तीन दिन की नई दिल्ली यात्रा से दोनों देशों को अपने वर्षों पुराने संबंध मजबूत बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने का एक और मौका मिला. पूरी यात्रा पर रूसी नेता की छाप साफ दिखाई दे रही थी. पर राजनयिक औपचारिकताओं के पीछे यह भाव भी देखने में आया कि रिश्तों में एक धीमा किंतु महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है. रूसी नेता की यात्रा के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण:

दृश्य हर बार यही रहता है, जैसे एक ही कलाकार इसे बनाता हो. हर बार मिखाइल गोर्बाचेव और राजीव गांधी इसी तरह गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं और भारत-सोवियत रिश्ते को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं. लेकिन इस बार गोर्बाचेव की दूसरी दिल्ली यात्रा कुछ अलग किस्म की थी.

सोवियत महोत्सव का समापन कार्यक्रम हालांकि भव्य था पर जिस समारोह में गोर्बाचेव को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया वह बहुत सादगीपूर्ण रहा. हालांकि भारत मेजबान था पर इस दौरे पर रूस के आलाकमान गोर्बाचेव की ही छाप थी. यहां तक कि उन्होंने भारतीय मेजबानों को पहले से ही बता दिया था कि वे दौरे के आखिर में होने वाला परंपरागत संवाददाता सम्मेलन नहीं करेंगे.

जाहिर है, गोर्बाचेव राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद इस पहले भारत दौरे का बहुत तामझाम नहीं चाहते थे और जहां तक संभव हो इसे द्विपक्षीय संबंधों के आधार के अनुरूप ही पूरा करना चाहते थे. उनके साथ आए नेताओं के चयन से भी यही जाहिर हुआ. नवंबर 1986 में जब वे भारत आए तो उनके साथ 110 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल था. जबकि इस बार उनके साथ सिर्फ वही लोग आए जिनका उनके साथ होना कार्यक्रम के मुताबिक जरूरी था. इन लोगों में विदेशमंत्री एडुअर्ड शेवर्दनात्जे, भारत सोवियत संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्ष, उप-प्रधानमंत्री एम.वी. कामेंतसेव, विदेश व्यापारमंत्री के.एफ. कातुचेव, उप-विदेशमंत्री और एशिया के प्रभारी इगोर रोगचेव और सांस्कृतिक कार्यमंत्री व सोवियत-भारत महोत्सव समिति के सह-अध्यक्ष वी.जी. ज़कारोव थे. प्रतिनिधि मंडल में एकमात्र उच्चस्तरीय सदस्य थे—उज़बेकिस्तान के प्रथम सचिव.

लेकिन भारत-सोवियत रिश्तों में आए मामूली लेकिन अहम बदलाव के परिप्रेक्ष्य में इस दौरे को कम करके नहीं आंका जा सकता. दोनों नेताओं की अनौपचारिक टिप्पणियों ने जो असर बनाया वह पहले से तैयार भाषणों तथा साझा बयानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था. लेकिन एक बात बहुत साफ थी, इस द्विपक्षीय मामले पर एशिया के एक और दिग्गज चीन का साया मंडराता रहा.

दो मौकों पर गोर्बाचेव ने इस 'गैर-दोस्ताना' अटकल पर काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भारत-सोवियत रिश्तों में अब वैसी गर्मजोशी नहीं रही. लेकिन हैरत की बात तो यह कि गोर्बाचेव की यात्रा से ठीक पहले छपे कुछ छिटपुट लेखों के अलावा ऐसी अटकलें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

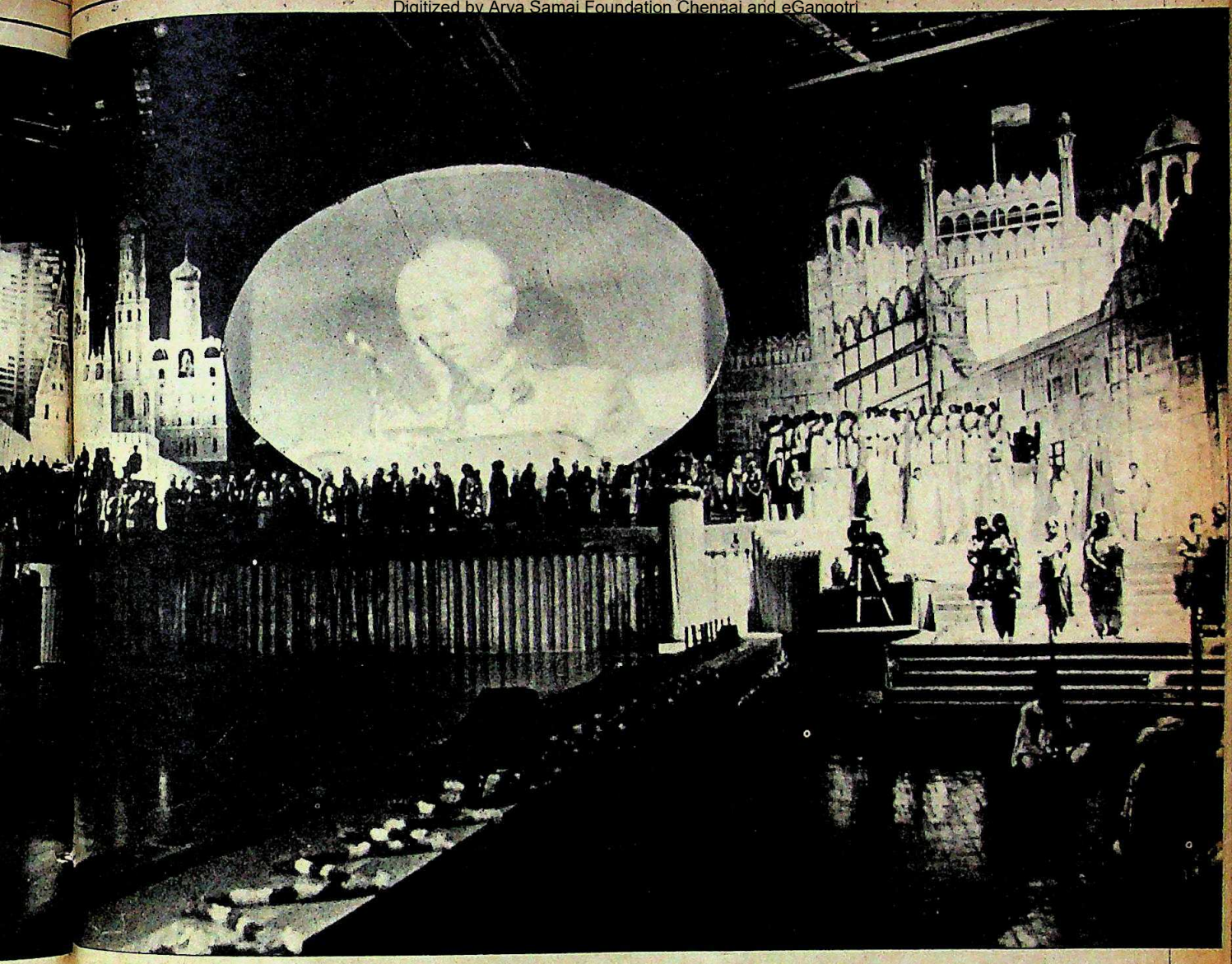

दिल्ली में सोवियत महोत्सव के समापन समारोह का भव्य दृश्य

इन दोनों नेताओं की अनौपचारिक टिप्पणियों ने जो असर बनाया वह पहले से तैयार भाषणों और साझा बयानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था

किसी ने नहीं लगाई. और फिर इन लेखों की टिप्पणियां इतनी अहम भी नहीं थीं कि गोर्बाचेव जैसे नेता को उन पर ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ता. फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि रूसी नेता को बचाव का रुख अख्तियार करना पड़ा?

'इंडिया टुडे' को पता चला है कि इस तरह की 'अटकलें' दौरे से पहले इंका के ही कुछ हलकों में लगाई गई थीं और गोर्बाचेव ने भारत सरकार के अनुरोध पर दोस्ताना रिश्तों वाली टिप्पणी की. सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ दल के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को लग रहा था कि गोर्बाचेव की अगुआई में सोवियत विदेश नीति में आए बदलाव से उसकी अंतरराष्ट्रीय रणनीति में भारत की भूमिका नगण्य रह जाएगी. इस अंदेशे का आधार यह था कि मास्को और पेइचिंग के सुधरते रिश्तों का असर अंततः भारत-रूस संबंधों पर पड़ेगा.

सत्तारूढ़ पार्टी के हलकों में ऐसा सोचा जा रहा था. यह बात राजीव के संसद में दिए बयान से भी जाहिर हो गई. उन्हें कहना पड़ा कि "रूसी-चीनी और भारत-सोवियत रिश्ते एक-दूसरे से अलग-अलग हैं." और "एक की कीमत पर किसी दूसरे के होने का सवाल ही नहीं उठता." उन्होंने यह भी कहा कि चीन के साथ भारत की सीमा समस्या पर दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई.

संयुक्त बयान में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि चीन का नाम इससे अलग रहे. पर छुपाने की कोशिश में यह मामला सामने आ ही गया. सारी राजनयिक कोशिशों के पीछे की सचाई यह है कि सोवियत-चीनी रिश्ते सुधरने का असर भारत-सोवियत रिश्तों पर पड़ेगा जरूर. मास्को-पेइचिंग रिश्तों में आए नाटकीय बदलाव की परिणति अगले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोवियत महोत्सव

शानदार समापन

यह प्रेम और शांति का मिश्रण था. सबसे पहले प्रेम की बात. भारत में साल भर चले सोवियत महोत्सव के लिए आए, 3,700 टन माल असबाब की एक-एक चीज में प्रेम ही टपकता था. पिछले ही पखवाड़े इस महोत्सव का समापन समारोह बड़ी धूमधाम से हुआ. मास्को ने साल भर अपने यहां के अलौकिक बोलशोई और किरोव बैले से लेकर रंगारंग सर्कस सरीखे चुनिंदा कार्यक्रमों से भरे प्रेम के अपने अथाह झोले को मानो पूरे का पूरा ही उकेर दिया.

अब बारी शांति के प्रतीक कबूतरों की थी. समापन समारोह के दौरान ये शांति प्रतीक अपने साथ शांति संदेश भी लाए. मानो वे राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के दिल की बात कह रहे हों. स्केटिंग करती महिला द्वारा हाथ में लिए शांति प्रतीक के ऊपर बाज आ बैठा. कबूतर ठीक इसके नीचे बैठा था. आगे एक ग्लोब पर तीन कबूतर मंडरा रहे थे. अचानक एक कबूतर बाज को हराकर शांति प्रतीक पर जा बैठा. दूसरे कबूतर ने भी नीले ग्लोब पर कब्जा जमा लिया. शांति की जीत हो गई. अंकल सैम (अमेरिका) टापते रह गए.

उत्सव की शुरुआत जितनी धमाकेदार हुई, समापन भी उतना ही धमाकेदार रहा. इस दौरान जादू-सा छाया रहा. यह साल ही यादगार साबित हुआ. सांस्कृति धरोहरों की तीन उम्दा और दुर्लभ प्रदर्शनियां आयोजित हुईं. तीन सर्कसों के यादगार प्रदर्शन हुए—मास्को आइस बैलेट, बोलशोई और किरोव बैलेट्स नाटक न जॉज ग्रुप, पॉप गायकों और दूसरे कई प्रकार के कलाकारों ने अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया. पूरे आयोजन में 62 में से 26 ग्रुप लोक गायकों और नर्तकों के थे.

सोवियत कारवां भारत के 162 शहरों और कस्बों तक गया.

एपीएन

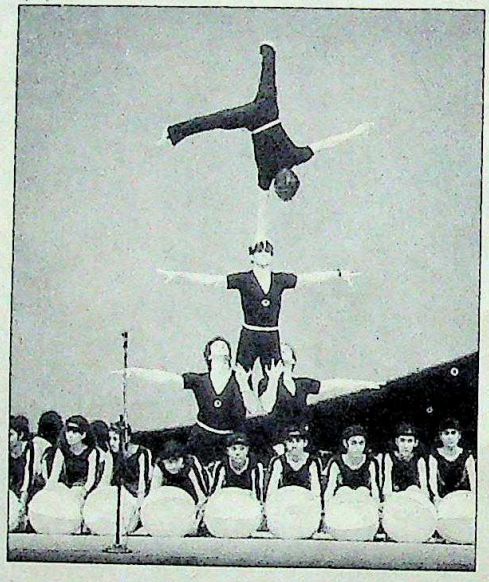

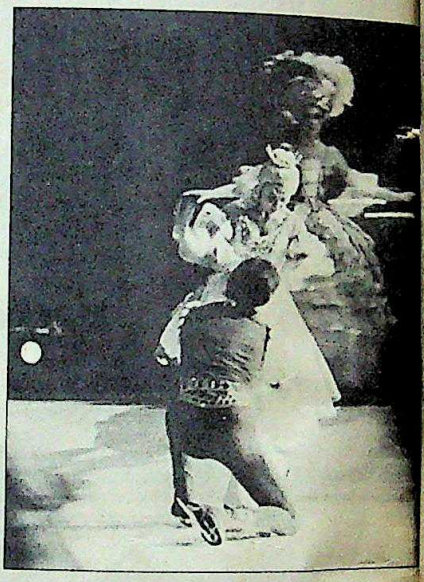

(ऊपर बाएं से) कलाकारों के करतब; बर्फ पर बैले; और (नीचे) एक लोक नृत्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करोड़ों लोगों ने इसके करतब देखे. यह विशालता के साथ-साथ खूबसूरती भी समेटे था. महोत्सव में बराबरी की भावना के मुताबिक रूसियों ने 2,400 कलाकार भेजे. भारत ने भी करीब इतने ही कलाकार रूस भेजे थे. शिकायत केवल यह रही कि रूसी कारवां कुछ ज्यादा ही बड़ा था. अच्छाई की यह पराकाष्ठा थी.

कार्यक्रम बंबइया सिनेमा की तरह चकाचौंध भरा था. अधर में लटकी कंदीलें बड़े रहस्यात्मक तरीके से बर्फ पर थिरक रही थीं मानो अदृश्य हाथों से उन्हें चलाया जा रहा हो. कुछ कंदीलें तो अचानक काफी दूर तक आगे सरक गईं. सात स्तरों वाले मंच पर नाच और कलाबाजी का आलम छा गया था. नीचे की तरफ चमत्कृत भारतीय दर्शक बैठे थे. अंडाकार विशाल परदे पर कार्यक्रम के बेहतरीन हिस्सों और अहम घटनाओं—दिल्ली घोषणा, दोनों देशों के नेताओं की यात्रा और लेनिन को दिखाया जा रहा था. इस सबके बीच क्रेमलिन और लाल किले के दीप्तिमान कटआउट्स मानो परदे पर दिखाई जा रही बातों के गवाह हों. आगे बार और ट्रांपोलाइंस लगे थे जहां ओलंपिक जिमनास्ट इलेना शुशुनोवा, दिमित्री बिलोजेरचेव और व्लादीमीर आर्तेमोव ने अपनी-अपनी क्षमता का परिचय दिया.

जल्दी ही अपनी तरह के खास कार्यक्रम हिंदी-रूसी जुगलबंदी की बारी आई. माहिर और व्यावसायिक कलाकारों के साथ मैले-कुचैले और बेतरतीब चुन्नटों वाली सलवार-कमीज पहने भारतीय नृत्यांगनाएं मुरझाए हुए फूल सरीखी नजर आईं. उनका प्रदर्शन स्कूली कसरत का महज परिष्कृत रूप नजर आया. रूसियों ने 200 भारतीय लड़कों और लड़कियों को और आनंद शंकर ग्रुप को नृत्य रचना में शामिल किया था.

भारत की तरफ से जॉर्ज माइकल के चमत्कारी संस्करण, गोवा के पॉप गायक रेमो फर्नांडीस ने अकेले दिल जीत कार्यक्रम पेश किया. उन्होंने अपने गीत "टेक मी बैक टू मास्को. इट इज द प्लेस आई वांट टू बी..." (मुझे वापस ले चलो मास्को. यही जगह है जहां मैं...) से अलग ही प्रकार का समां बांध दिया.

यही वह जगह है जहां वे जल्द ही जाएंगे. महोत्सव का एक अप्रत्याशित नतीजा रहा पॉप गायकों के एक दूसरे देश में व्यावसायिक कार्यक्रम. भरतनाट्यम के बजाय अब सीबीएस अगली फरवरी में सोवियत संघ में फर्नांडीस के संगीत कार्यक्रम आयोजित कर रही है. और भारत में तहलका मचा देने वाले रूसी पॉप गायक वालेरी लिओंतिफ इस महीने के आखिर में भारत के छह शहरों का दौरा शुरू करेंगे. दोनों के रिकार्ड सीबीएस तैयार करेगा.

विडंबना ही है कि दो पुराने दोस्तों का मिलन अब पॉप संगीत पर होगा. महोत्सवों को बाधाओं के बावजूद कामयाब बनाने और थकान की शिकन तक पास न फटकने देने वाले भारत महोत्सव के महानिदेशक दलजीत अरोड़ा का कहना है, "हमने रूसियों को साफ-साफ बता दिया था कि यदि वे भारत के युवाओं तक पहुंचना चाहते हैं तो वे रॉक और जैज की उपेक्षा नहीं कर सकते. उनके देश के बारे में जो नीरस छवि हमारी नजरों में है, वह दूर होनी चाहिए. इसी तरह ग्लासनोस्त युग में रूसियों में भारत की छवि भी बदलनी होगी. शास्त्रीय संगीत जरूर हो, मगर पॉप संगीत भी."

दोनों महोत्सवों का अब समापन हो गया है. भारतीय राजकोष से 41 करोड़ रु. या इससे अधिक खर्च हुए होंगे. लेकिन जो सद्भावना उपजी वह इससे भी कहीं कीमती है. रूसियों की भी वह पुरानी छवि बदली है. उन्होंने भी बदलते वक्त के साथ कदम मिलाना सीख लिया लगता है.

—मधु जैन

साल के शुरू में चीन-सोवियत शिखर सम्मेलन में होने जा रही है और इससे दोनों को ही फायदा होने की उम्मीद है. एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक कहते हैं, "हमारा मानना है कि मास्को और पेइचिंग के रिश्ते काफी सुधरेंगे. चीनियों को अब लगने लगा है कि अमेरिका तो उन्हें 'दाल बराबर' समझता है. मास्को से घनिष्ठ संबंध बनाने पर उन्हें आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में दीर्घकालिक फायदा मिल सकेगा. गोर्बाचेव उन्हें काम के आदमी लगते हैं."

असल में गोर्बाचेव ने राजीव गांधी से नौ घंटे की बातचीत में चीन-सोवियत रिश्तों के मौजूदा और भावी स्वरूप के बारे में गहन विचार-विमर्श किया. इस दौरान उन्होंने भारत-चीन रिश्ते सुधारने की जरूरत पर भी बल दिया. यह ठीक है कि भारत की चीन से सीमा विवाद पर कोई बातचीत नहीं हुई पर इसकी वजह थी चीन का पेचीदा रुख. अगले महीने राजीव गांधी की प्रस्तावित चीन यात्रा के सिलसिले में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल तीन बार चीन का दौरा कर चुका है. इसका आखिरी दौरा गोर्बाचेव की नई दिल्ली यात्रा के तुरंत बाद हुआ. इस प्रतिनिधि मंडल में विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन, राजीव गांधी के दो प्रमुख सलाहकार—गोपी अरोड़ा और प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव रोनेन सेन शामिल थे.

पर चीन ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं. राजीव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी यात्रा के दौरान सीमा विवाद उठाने की कोशिश नहीं की जाएगी. यानी जहां तक भारतीय पक्ष का सवाल है, 1954 में हुई पहली भारत-चीन शिखर वार्ता के अंतिम नतीजे अनिश्चितता के घेरे में ही बने रहेंगे.

लेकिन भारतीय अधिकारी यह बताने से नहीं चूकते कि चीन-रूस की प्रस्तावित शिखर वार्ता के तुरंत बाद दोनों देशों के रिश्तों में कोई नाटकीय बदलाव नहीं आ जाएगा. नए समीकरण बनने में कुछ समय लगेगा. इसलिए चीन से रूस के रिश्ते सुधरने के कारण अगले कुछ साल तक भारत-सोवियत संबंधों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

पर गोर्बाचेव की यात्रा से एक बात जरूर जाहिर हो गई कि भारत-सोवियत रिश्तों में हल्का-सा बदलाव आ चुका है. उच्च स्तर पर संबंधों की गर्मजोशी और नजदीकी अभी बनी हुई है. लेकिन यह घनिष्ठता किसी योजनाबद्ध नीति का नहीं बल्कि राजीव और गोर्बाचेव की पिछली चार मुलाकातों का परिणाम है. ये संबंध आज की वास्तविकताओं और तेजी से बदल रहे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर आधारित हैं. इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रिश्ते अतीत की सैद्धांतिक हठधर्मिता से आक्रांत नहीं हैं. मिसाल के लिए गोर्बाचेव जानबूझकर दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं से नहीं मिले. वरना पहले किसी भी सोवियत नेता की यात्रा में यह एक जरूरी कर्मकांड होता था.

रूसी नेता की इस यात्रा से स्पष्ट हो गया कि सोवियत संघ में और खासकर उसकी विदेश नीति में हुए ताजा बदलाव भारत-सोवियत रिश्तों को बदल तो नहीं सकते पर बदलाव में मददगार हो सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजनैतिक रिश्ते तो यथावत रहेंगे, अब ज्यादा जोर आर्थिक मामलों पर दिया जाएगा.

इस यात्रा में हुए व्यापक आर्थिक समझौतों से इसकी झलक मिलती है. रूसियों ने भारत को अब तक का सबसे ज्यादा कर्ज (3.2 अरब रूबल) दिया है. मुख्य ध्यान अब परंपरागत क्षेत्रों के बजाय परमाणु व तापीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीक, नागरिक उड्डयन और पेट्रोरसायन के क्षेत्रों में सहयोग पर दिया जा रहा है. एक अधिकारी का कहना है, "भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रूसी दृढ़संकल्प दिखते हैं. '50 और '60 के दशक में इस्पात तथा भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया. उसके बाद उन क्षेत्रों में सहयोग मिला जिनमें हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे. वे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दीर्घकालिक सोच के साथ संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं.

इस अर्थ में यह कहना वाजिब ही था कि संबंध अब और प्रगाढ़ हुए हैं. भारतीय प्रतिनिधि के अनुसार, "रिश्ते अब इतने परिपक्व हो चुके हैं कि कोई पक्ष दूसरे को कमतर करके नहीं आंक सकता." मिसाल के लिए गोर्बाचेव ने जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय तथा उसके अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की बात उठाई और राजीव पर परमाणु परिसीमन संधि पर दस्तखत के लिए दबाव डाला तो राजीव ने इनकार कर दिया. इसके बाद गोर्बाचेव ने ज्यादा जोर नहीं दिया और मामला टाल दिया.

पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों ने अलग से विचार करने के बजाय अफगानिस्तान के संदर्भ में गहन विचार किया. एक भारतीय अधिकारी के अनुसार, "समस्या का निदान स्वयंमेव होने तक दोनों ही पक्ष 'देखो और इंतजार करो' वाली नीति अपना रहे हैं. क्योंकि अनिश्चित स्थिति पर बहस कर वक्त बरबाद करने से क्या लाभ?"

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया के बारे में गोर्बाचेव के नए दृष्टिकोण और सोवियत संघ की विदेश नीति पर इसके असर ने मास्को की कूटनीतिक प्राथमिकताएं बदल दी हैं. अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान से नए संबंध बनाने के अलावा सोवियत संघ अफगानिस्तान, विएतनाम, अंगोला, निकारागुआ व क्यूबा जैसे मसलों को सुलझाने के लिए भी उत्सुक है.

इस संदर्भ में सोवियत कूटनीति में भारत का महत्व ब्रेझनेव युग के मुकाबले कम हो सकता है. भारत ने उदारता से इस परिवर्तन को कबूल भी कर लिया है पर भारत को विश्वास है कि सोवियत संघ से प्रगाढ़ हो चुके संबंध और गोर्बाचेव और राजीव गांधी के निजी संबंध दोनों पक्षों के बीच विश्वास और आदर की भावना बनाए रखने का मजबूत आधार प्रदान करते रहेंगे. —दिलीप बॉब

'हमारी गोष्ठी'

रहस्यमय लोकप्रियता

एक तरफ चुप-चुप रहने वाली सोनिया गांधी और दूसरी तरफ कुछ-कुछ बातूनी डॉ. नज्मा हेपतुल्ला के बीच बैठी सोवियत संघ की प्रथम महिला रईसा गोर्बाचेव अपनी मानस पुत्री—भारत-सोवियत महिला पत्रिका 'डायलॉग' की सफलता का बखान कर रही थी. इस पत्रिका का प्रकाशन दो साल पहले रईसा की भारत यात्रा के बाद किया गया था. सोवियत संघ में इस पत्रिका की अभूतपूर्व लोकप्रियता और प्रशंसात्मक पत्रों का ब्यौरा देते समय रईसा का चेहरा उत्साह से दमक रहा था.

'डायलॉग' के अंग्रेजी संस्करण 'हमारी गोष्ठी' का कोई अता-पता नहीं है. हालांकि इस त्रैमासिक पत्रिका के छह अंक निकल चुके हैं लेकिन वहां बैठी महिलाओं को, जिनमें से कुछ तो पत्रिका के संपादक मंडल में भी रही हैं. इस पत्रिका की पूंजी और बिक्री के बारे में कुछ पता नहीं था. कुछ महिलाओं का अनुमान था कि इस पत्रिका की प्रसार संख्या 5,000 से 7,000 के बीच है लेकिन नज्मा का दावा था कि प्रसार संख्या 10,000 है.

राज्यसभा की उपसभापति नज्मा ने कुछ रहस्यों पर से परदा उठाते हुए बताया कि 'हमारी गोष्ठी' तो दरअसल उनकी मानस पुत्री है. पत्रिका के कुछ आरंभिक अंक उन्होंने निजी पैसों और मित्रों से मिली आर्थिक मदद से निकाले. जबकि इसके रूसी संस्करण का प्रकाशन रईसा की देखरेख में सोवियत नोवोस्ती प्रेस ऐजेंसी द्वारा होता है.

सोनिया, रईसा और हेपतुल्ला; (नीचे) पत्रिका की प्रतियां

एपीएन

इस पत्रिका का ताजा अंक चिकने कागज पर निकाला गया था. इस बार हेपतुल्ला को विज्ञापन और फंड के रूप में आर्थिक सहायता मिली. वे कहती हैं, "अब जाकर घाटा खत्म हुआ है." इतनी ही सफलता से उत्साहित नज्मा अब इसके हिंदी संस्करण की योजना बना रही हैं. एअर इंडिया को कुछ प्रतियां बेचने की कोशिशें भी जारी हैं. एअरोफ्लोत (सोवियत वायु सेवा) और कुछ पूर्व यूरोपीय देशों में भी यह बिकती है.

पैसा कोई बड़ी समस्या नहीं है. पत्रिका की डमी मास्को में तैयार की जाती है. नज्मा बताती हैं, "हमें कुछ लेख तैयार करके यहां से मास्को भेजने होते हैं और वहां से वे जो कुछ हमें भेजते हैं, हम यहां छाप देते हैं."

'डायलॉग' की एक प्रति की कीमत 80 कोपेक (13 रुपए) है. पत्रिका की प्रमुख संपादक हैं सोवियत संघ की महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंतीना तेरेश्कोवा. पत्रिका की डिप्टी एडीटर-इन-चीफ — मरीना ब्लागोनरावोवा कहती हैं, "सोवियत संघ में यह पत्रिका 66 शहरों में बिकती है. हमारे पाठकों की भारतीय कला और संस्कृति में गहरी रुचि है. हमारे पास भारत के फिल्मी सितारों — जीनत अमान, मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन—पर लेख प्रकाशित करने की फरमाइशें आती रहती हैं. उक्रेन के पाठकों ने तो दीवार पर टांगने का एक चित्र भी भेजा है जिस पर 'हमारी गोष्ठी' नाम काढ़ा गया था. रूसी पत्रिका की इस लोकप्रियता और अपनी असफलता पर रईसा के साथ बैठी भारतीय महिलाएं अगर शर्म से लाल हो रही हों तो क्या अचरज?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एकमात्र भारतीय प्रेशर कुकर जो यूरोप एवं अमेरिका के बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स में बिक रहा है

ब्लूमिंग्डेल्ज़, न्यू यॉर्क. बुलक्स, लॉस एन्जेल्स. डेटन-हडसन, डेट्रॉयट. कारसन पाइरी स्कॉट, शिकागो. वुडवर्ड एण्ड लॉथ्रॉप, वॉशिंगटन. बर्डिंग्स, मियामी. मैसीज़, सैन फ्रांसिस्को. सेलफ्रिजेस, लंडन. इन्नोवेशन, ब्रसेल्स. बेयेनकॉर्फ़, एमस्टरडम. सिमागो, मैड्रिड... ये और दुनिया के अन्य नगरों के कई आलीशान स्टोर्स में हॉकिन्स के फ़्यूचुरा प्रेशर कुकर बेचे जाते हैं.

आप भी विश्व के सबसे खूबसूरत और टिकाऊ प्रेशर कुकर ख़रीद सकते हैं. हॉकिन्स फ़्यूचुरा ५ लीटर – रु. ६१९/, ७ लीटर – रु. ७४३. हॉकिन्स फ़्यूचुरा के निकटतम विक्रेता की जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर लिखिए.

हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड, डिपार्टमेंट नं. १२०, उद्योग मंदिर नं. २, तीसरा माला, ७ सी, पीताम्बर लेन, माहीम, बंबई-४०० ०१६. प्रेशर कुकर की ये कीमतें बिना सेपरेटर्स के हैं. अधिकतम कीमत, स्थानीय कर अतिरिक्त ® पंजीकृत ट्रेड मार्क हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड द्वारा कॉपीराइट सुरक्षित १९८८.

डिज़ाइन और निर्माण की जिस उत्कृष्टता के कारण हॉकिन्स फ़्यूचुरा को विश्वभर में पसंद किया जाता है वही उत्कृष्टता परम्परागत हॉकिन्स प्रेशर कुकर में भी पाई जाती है.

हॉकिन्स प्रेशर कुकर्स २ लीटर, रु. २१२/- □ ३ लीटर, रु. २६७/- □ ४ लीटर, रु. ३१०/- □ ५ लीटर, रु. ३३४/- □ ६.५ लीटर, रु. ३७२/- □ ८ लीटर, रु. ४२१/- □ १० लीटर, रु. ५०७/- □ १२ लीटर, रु. ५९४/-. और २२ लीटर, रु. १,१२७.

अपनी आवश्यकता का हॉकिन्स चुनिए. दुनिया का उत्कृष्ट कुकर लीजिए. हॉकिन्स ही लीजिए.

हॉकिन्स®
फ़्यूचुरा™
प्रगतिशील पीढ़ी का प्रेशर कुकर

HC/3799/6/R

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बेनज़ीर भुट्टो

नई जिम्मेदारियां

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंजिले मकसूद तक आखिर वे पहुंच गई हैं. लंबा और थकाऊ सफर आखिर खत्म हो गया है. उथल-पुथल भरे पूरे 11 वर्षों तक जो लक्ष्य किसी आकाशदीप की तरह हमेशा उनकी राहों को जैसे रोशन करता रहा, आज उसी मील के पत्थर को उन्होंने फतह कर लिया है. बेनज़ीर आज इतिहास के एक अहम मोड़ पर पहुंच गई हैं.

इस कामयाबी का सेहरा उनका ही है, सिर्फ उनका ही. कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता क्योंकि इसका हकदार उनके सिवा दूसरा कोई नहीं. मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही यह 'पूरब की बेटी' (अपनी जीवनी उन्होंने इसी नाम से लिखी है) जिस तेजी, कुशलता और परिपक्वता से पाकिस्तानी राजनीति पर छा गई है उससे तो यही लगता है जैसे उसकी नियति यही थी.

परी कथा जैसी उनकी जीवनकथा की नियति और हो भी क्या सकती थी? लेकिन इस जीवन का वह रुमानी अध्याय अब समाप्त हो गया है. बेनज़ीर आज अगर अपने लक्ष्य से रू-ब-रू हैं, तो उन्हें

चंद हफ्तों में ही बेनज़ीर की बिलकुल अलग छवि निखरी. उन्होंने ऐसी विशेषताओं का प्रदर्शन किया जो नेताओं को औरों से बीस साबित करती है

वास्तविकताओं का भी सामना करना है. पिता की विरासत की जिम्मेदारी निभाना कठिन चुनौती होती है. बेनज़ीर के लिए तो यह और भी कठिन चुनौती है—पुरुष प्रधान समाज में महिला होने के कारण ही नहीं, एक इस्लामी राज्य में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोने के कारण भी.

1986 की गर्मियों में पाकिस्तान लौटने के बाद उनका उत्साह थोड़ा मंद पड़ गया था और वे सब कुछ जैसे भाग्य भरोसे छोड़ देने को तैयार हो गई थीं. तभी किस्मत भी जैसे अपनी भूमिका निभाने को तैयार दिखी. बहावलपुर में पाक वायुसेना के सी-130 विमान की दुर्घटना में जनरल जिया-उल-हक की मृत्यु हो गई. इसके बाद बेनज़ीर ने बड़ी तेजी के साथ जो कदम उठाए वे एकदम सही थे. उनसे बड़े और अनुभवी नेता जबकि गठजोड़ बनाने और रणनीतियां तय करने में मशगूल थे, बेनज़ीर ने चुनाव अभियान का बिगुल बजा दिया. इससे उनकी

कराची का जनसमुद्र: बेनज़ीर की पूंजी

लेम: रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कितना मधुर!

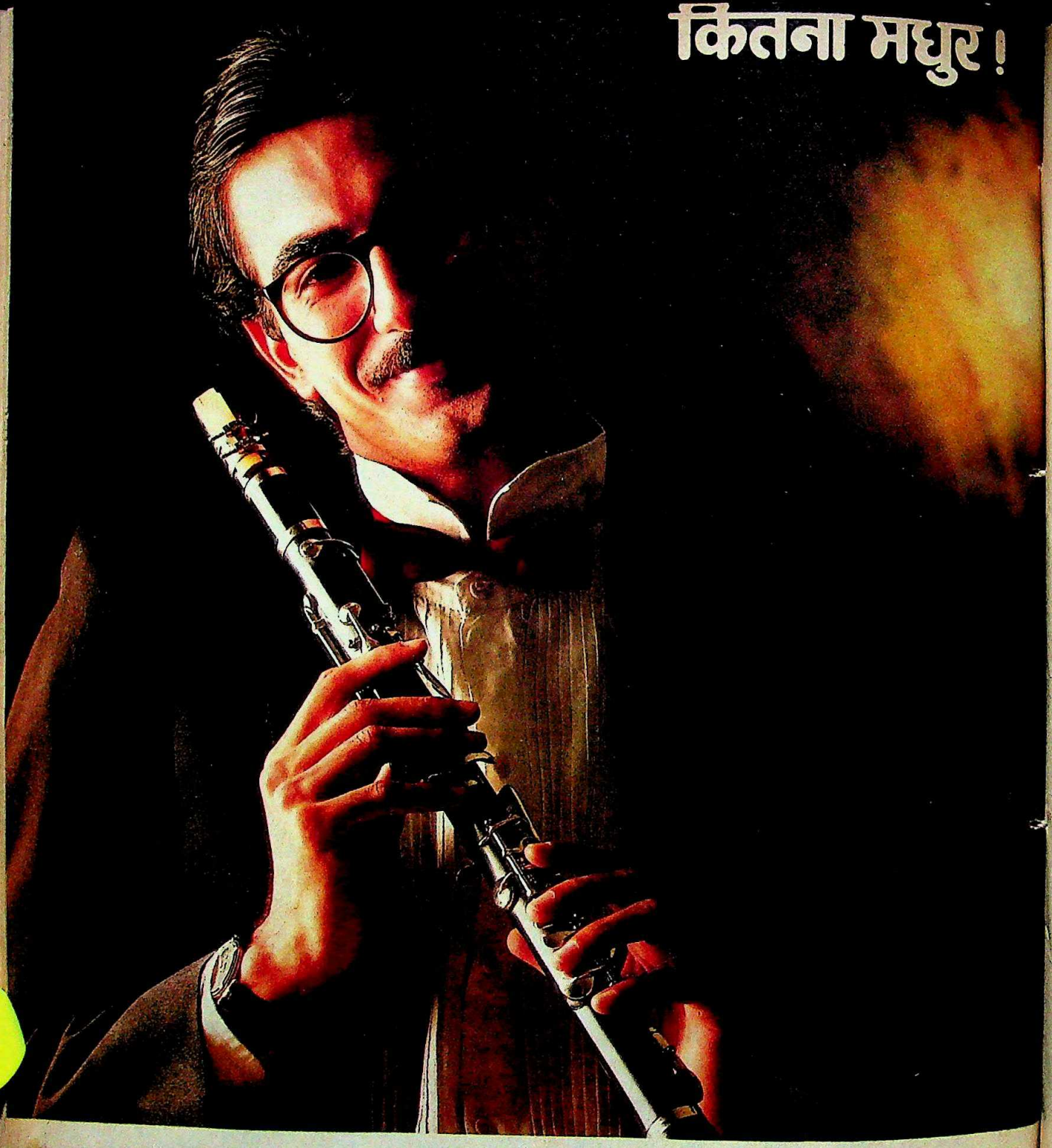

अपनी नयी धुन के सुर संजो रहा था तभी ठेकेदार ने सिमेंट की बात छेड़ दी। ने लगे जे के सिमेंट राजस्थान के सबसे बढ़िया लाइमस्टोन और डेनमार्क की नयी तकनीक से तैयार किया जाता है। "वाह! क्या जुगलबँदी है" अचानक मेरे मुँह से निकला, "और कितना मधुर वर्णन।"

Shems/6992

SUPER JK CEMENT

जीवन की धूप-छाँव में हमेशा आपके साथ

सुपर जे. के. सिमेंट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिलकुल अलग ही छवि निखरी. वे एक आजाद ख्याल वाली नेता के रूप में उभरीं. उन्होंने उन दो विशेषताओं का प्रदर्शन किया जो नेताओं को औरों से बीस साबित करती हैं. ये दो विशेषताएं हैं—करिश्माई व्यक्तित्व और अपूर्व साहस.

लेकिन बेनज़ीर के लिए आगे चुनौतियां और भी मुश्किल हैं. जिया की मौत ने भले ही उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचने का मौका दिया लेकिन जिया शासन की गड़बड़ियों की विरासत उन्हें इस शिखर से नीचे भी घसीट ला सकती है. सरकारी प्रोत्साहन से गहराए भ्रष्टाचार व अपराध से ग्रस्त समाज का उन्हें नेतृत्व करना है और उसे दिशा देनी है. और फिर, 'बंदूक, गुंडों और खुदा' का विरोध तो अच्छे से अच्छे वक्त में भी मुश्किल पैदा कर सकता है. लेकिन बदहाली के कगार पर पहुंचे देश में लोगों की दमित इच्छाएं आज उसी तरह बलवती हो उठीं हैं जैसे बोतल से निकला जिन्न हो. जातीय दंगों, अलगाववादी आंदोलनों, हेरोइन की तस्करी, हथियारों के खुले खेल और इस्लामीकरण के नाम पर पागलपन भरे अभियान ने मुल्क को विध्वंस के कगार पर ला दिया है. जातीय हत्याओं के निरंतर दौर के कारण कराची शहर का स्वरूप आज एकदम बदला हुआ है. सिंधी, मुहाजिर, बलूच और अब सेरैकी लोग भी पंजाबी प्रभुत्व वाले मुल्क से अलग होने या ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं. आज पाकिस्तान में 20 लाख लोग नशेड़ी हो गए हैं और हेरोइन की तस्करी में बड़े नामी परिवार भी शामिल बताए जाते हैं. यहां बात-बात पर हथियारों के मुंह खोल दिए जाते हैं. नाजायज हथियारों के तो भंडार जमा हो गए हैं.

बेनज़ीर को अब एक ऐसे समाज से निबटना है जिसे मध्यकालिक धर्मांधता और हिंसा की 'अफीम' दी जाती रही है. यह एक ऐसा समाज बन गया है जो अब इन्हीं बातों में अपना भविष्य देखने लगा है. लेकिन चुनाव के बाद कराची में जो अभूतपूर्व माहौल दिखा उससे कुछ उम्मीदें जगती हैं. कई दिनों तक हजारों नौजवान शहर की सड़कों पर सुबह से शाम तक जश्न मनाते रहे. इसे एक नई शुरुआत का संकेत माना जा सकता है.

पार्टी झंडा लहराते, नाचते, गाते और खुशियां मनाते युवकों—यहां तक कि युवतियों ने भी—अपनी आयातित टोयोटा और सुजुकी कारों में बैठकर शहर की सड़कों को सवेरे तक जाम किए रखा. यह एक स्वतःस्फूर्त लहर थी. 11 साल के इस्लामीकरण और तानाशाही शासन के खात्मे का जश्न था, आजादी की एक नई भावना का कबाइली दृश्य था जहां कि अब तक कट्टरपंथी और दकिया-

उनके प्रचारकों ने भुट्टो मां-बेटी को पंजाब-विरोधी और भारत-समर्थक घोषित किया. बेनज़ीर के उस कथित बयान को भी खूब प्रचारित किया गया कि वे प्रधानमंत्री के रूप में किसी पंजाबी का विरोध करेंगी

नक्शा: वी.के. शर्मा

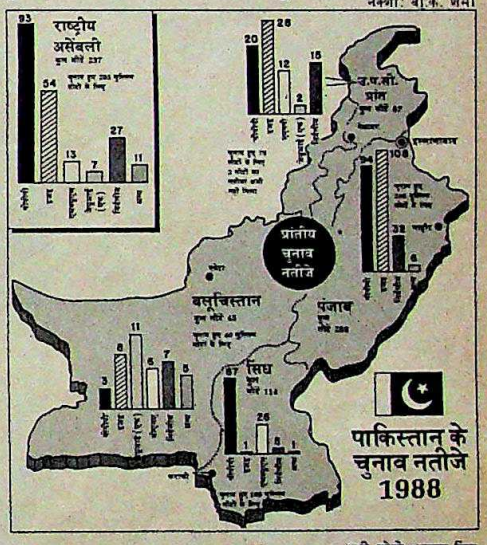

मतदान केंद्र पर औरतें: कम शिरकत

सभी फोटो: भवान सिंह

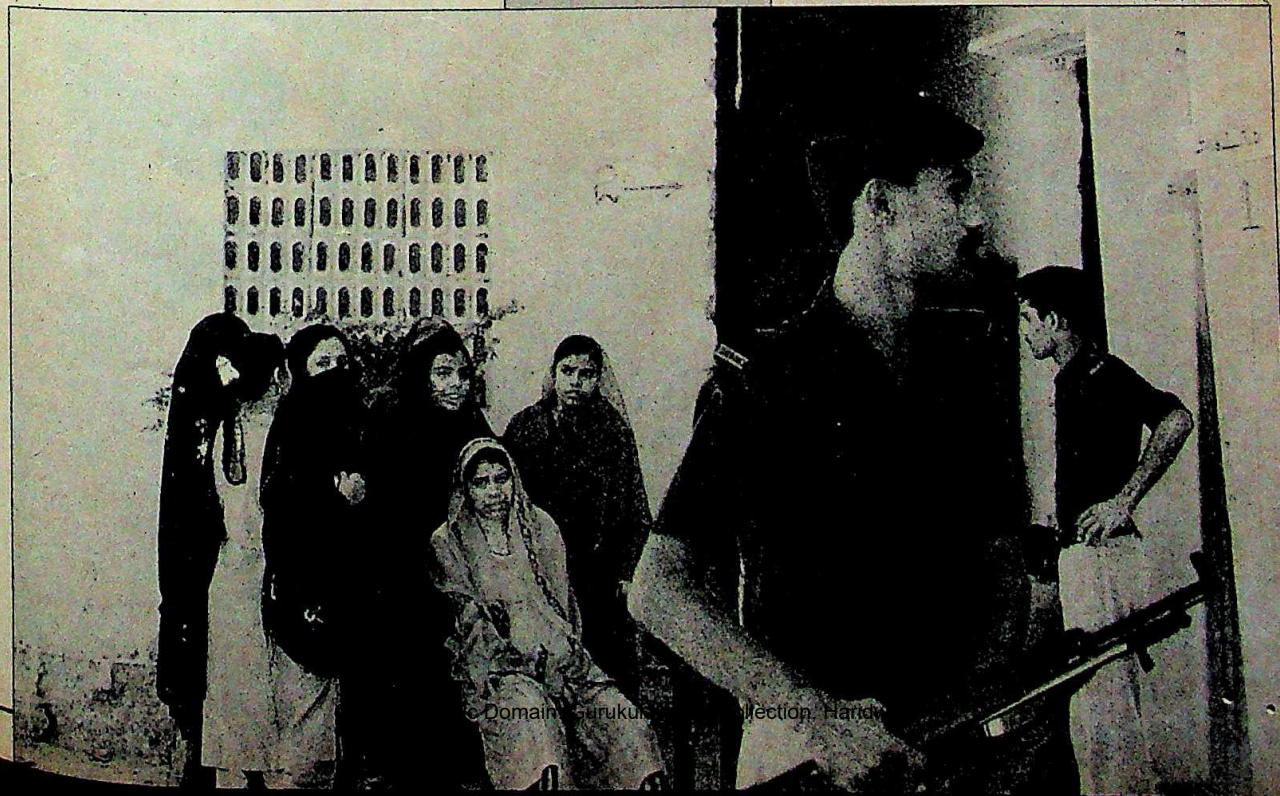

Shemsi6992
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नूसी जमात-ए-इस्लामी की ही तूती बोला करती थी.

राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों में मुहाजिर कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) की शानदार सफलता पर कराची के ज्यादातर हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा था. एमक्यूएम भारत से पाकिस्तान जा बसे लोगों का संगठन है और मुल्क की सियासत में अपेक्षाकृत नया ही माना जाता है. उच्चवर्गीय रिहायशी क्षेत्र क्लिफ्टन में बेनज़ीर भुट्टो के नए बंगले के आसपास के इलाके और उनके श्रमिक वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र ल्यारी की सड़कों पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के समर्थक भी जश्न मना रहे थे. युवा समर्थक बेनज़ीर के तीन मंजिले मकान के बाहर (इसका नाम उनके दो माह के बेटे बिलावल के नाम पर रखा गया है) नृत्य कर रहे थे और उनकी नेत्री गंभीरता और आत्मविश्वास से अपने सलाहकारों से राय-मशविरे में मशगूल थी. नजारा ठीक वैसे ही था जैसे कोई विजेता अपने सिपहसालारों से भविष्य की मंत्रणाएं कर रहा हो. और उनमें यह आत्मविश्वास इस तथ्य से आया कि उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोका जा सकता. बेनज़ीर की पीपीपी को राष्ट्रीय असेंबली में सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें ही नहीं मिलीं, बल्कि वह अकेली पार्टी है जिसके नुमाइंदे चारों प्रांतों की असेंबलियों के लिए चुनकर आए. और सिंध में तो एमक्यूएम और पीपीपी ने दूसरी पार्टियों को जैसे बुहार ही डाला. इस प्रांत में पंजाबी प्रभुत्व के खिलाफ सुलगते गुस्से का फायदा निश्चित ही इन दोनों पार्टियों को मिला है. ये हालात बताते हैं कि यदि बेनज़ीर को उनके वाजिब हक से महरूम किया गया तो मुल्क के टूटने के अंदेशे दिखने लगेंगे.

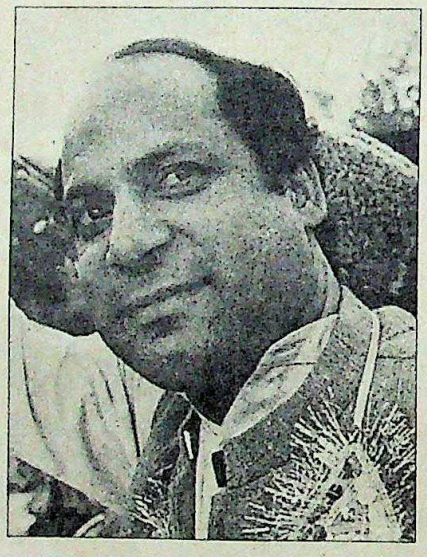

बेनज़ीर के घर के बाहर का माहौल इस बात का पर्याप्त सबूत था कि वक्त बदल गया है और यह भी कि पाकिस्तान के शासकों को अब नई सचाई कबूल करनी ही होगी. माहौल इतना खुशनुमा और सद्भावनापूर्ण था कि जश्न बिना किसी हिंसा या झड़प के रात भर चलता रहा. ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अंततः खून-खराबे और दमन के दौर से बाहर निकल रहा है. कराची के अंग्रेजी दैनिक 'डॉन' के सहायक संपादक गाजी सलाहुद्दीन की टिप्पणी थी, "परिवर्तन का असल नाटक कराची के मंच पर खेला गया. यह सांस्कृतिक मुक्ति का जश्न था."

लेकिन पाकिस्तान के राजनैतिक अहमियत वाले सूबे पंजाब की राजधानी लाहौर में वैसा उत्साह नहीं दिखा. इस सूबे में पीपीपी और सत्तारूढ़ इस्लामी जम्हूरी इत्तिहाद (इजइ) के बीच तनावपूर्ण और घटिया स्तर की चुनावी टक्कर हुई. पीपीपी के बढ़ते असर को रोकने की कोशिश में प्रांत के मुस्लिम लीगी मुख्यमंत्री नवाज़ शरीफ ने चुनाव अभियान के आखिरी हफ्ते में बेनज़ीर और उनकी मां नुसरत के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेपों का अभियान छेड़ दिया.

लेकिन इजइ के अभियान के असली अस्त्र थे—उद्धत राष्ट्रवाद और सूबाई भावनाएं भड़काना. उनके प्रचारकों ने भुट्टो मां-बेटी को पंजाब विरोधी और भारत समर्थक तक घोषित कर दिया. पीपीपी पर अमेरिकी यहूदियों, रूसियों और भारत द्वारा रची गई अंतरराष्ट्रीय सजिश का एजेंट होने का भी आरोप लगाया गया.

कई जिया समर्थकों को टिकट देकर सत्तारूढ़ जमात से बैर मोल न लेने की बेनज़ीर की कोशिश, पार्टी संगठन में कोई तारतम्य न रहने और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की सेवा से महरूम होने के कारण पीपीपी पंजाब में इजइ के दुष्प्रचार और आक्षेपों का जवाब ठीक से नहीं दी पाई.

इसके बावजूद पीपीपी राष्ट्रीय असेंबली के लिए पंजाब में इजइ से ज्यादा सीटें पाने मे कामयाब रही. इजइ की 44 सीटों के मुकाबले पीपीपी की झोली में 53 सीटें आईं. सिंध प्रांत में तो पीपीपी ने इजइ का सूपड़ा ही साफ कर दिया. लेकिन इन नतीजों से इजइ के इस आरोप को ही बल मिला कि पीपीपी बुनियादी तौर पर सिंध सूबे की ही पार्टी है.

फिर भी कुल मिलाकर चुनावी नतीजे बताते हैं कि पाकिस्तानी मतदाताओं ने बहुत ही सोच-समझकर और होशियारी से वोट दिए. सिंध के ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने अलगाववादी नेताओं और

नवाज़ शरीफ (बाएं); और लाहौर में इजइ के नेता: जीतोड़ कोशिश

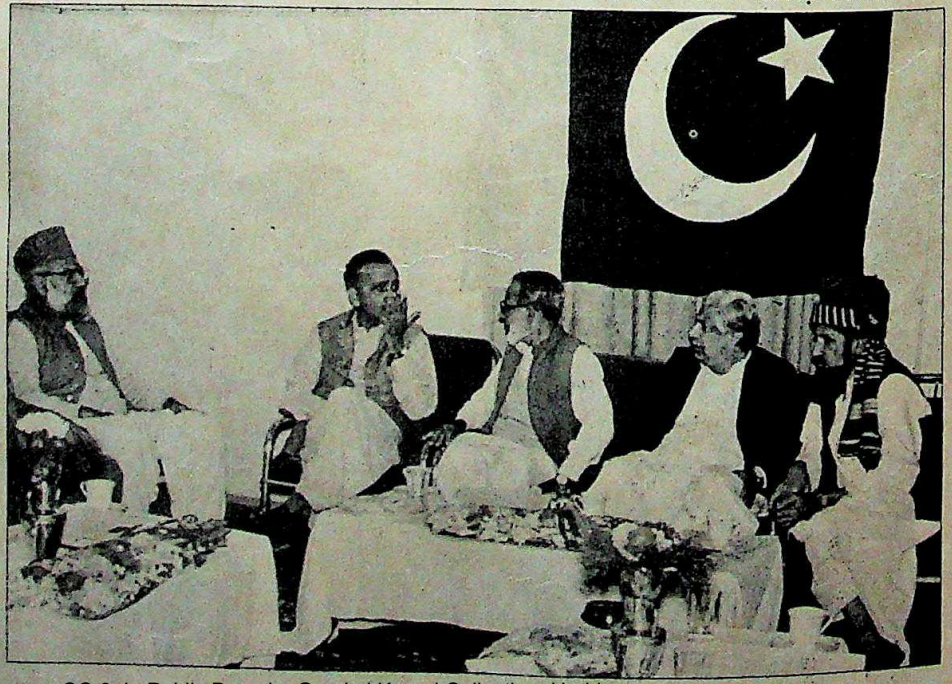

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनेक पात्रों से भरा
और जटिल शैली में लिखा गया महाकाव्य

महाभारत

अमर चित्र कथा में
सरल शैली
सुंदर चित्र
प्रामाणिक रूपांतर है

अमर चित्र कथा में प्रस्तुत है संपूर्ण महाभारत. अत्यंत रोचक एवं सरस 42 भागों में.

आज ही अखबारवाले के पास जाइए! या सदस्यता-छूट की जानकारी के लिए हमें लिखिए.

मूल्य: प्रत्येक 5 रुपये
अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, कन्नड़ व असमिया में

साथ ही उपलब्ध
- *त्रिवेणी अंक (3 भाग) प्रत्येक 16 रुपये*
- *पुस्तकालय संस्करण (6 भाग) प्रत्येक 40 रुपये*

अभी-अभी मुद्रित
- *वेदव्यास*
- *भीष्म प्रतिज्ञा*
- *पांडवों तथा कौरवों का जन्म*
- *पांडवों का हस्तिनापूर में आगमन*

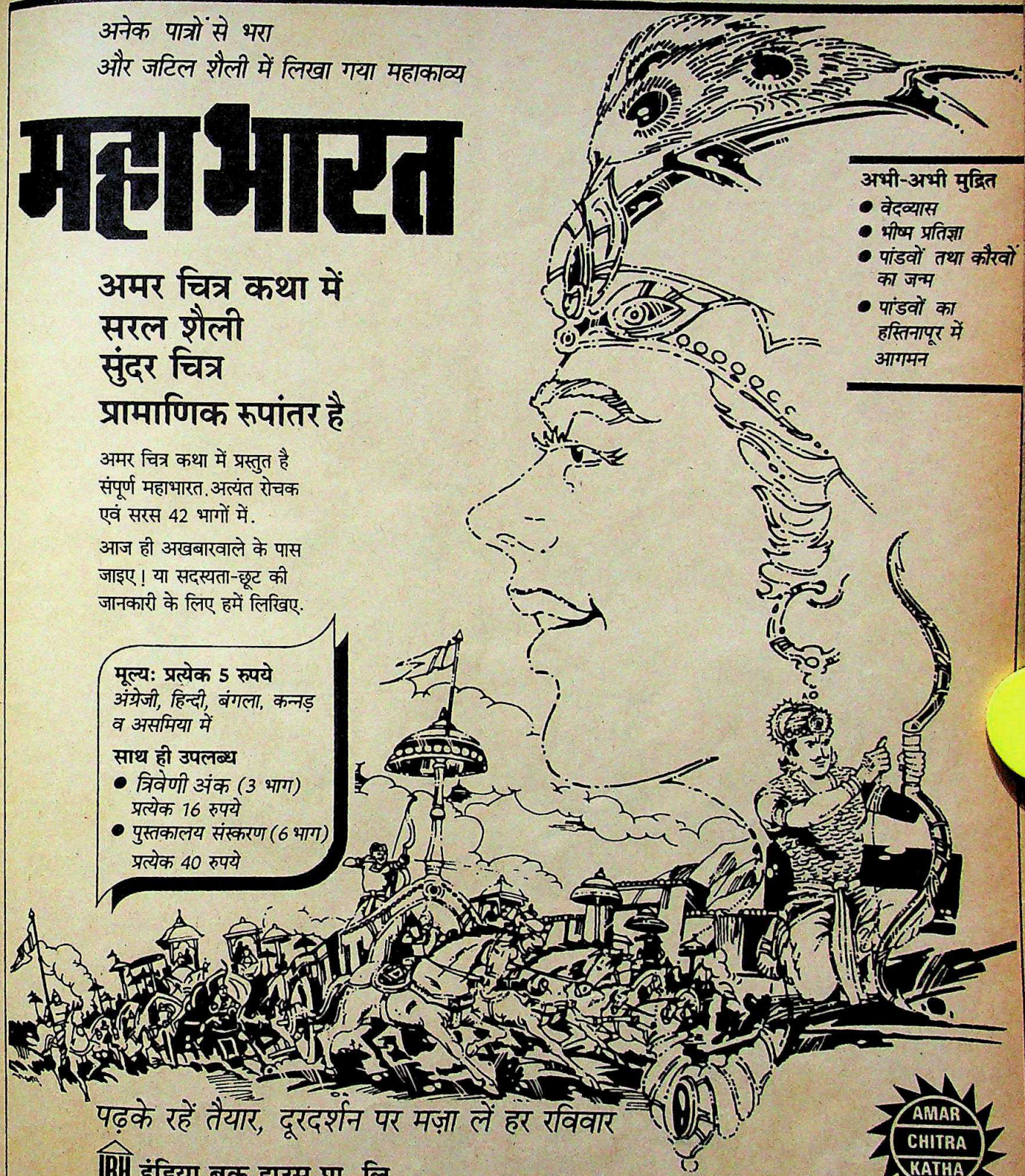

पढ़के रहें तैयार, दूरदर्शन पर मज़ा लें हर रविवार

AMAR CHITRA KATHA

IBH इंडिया बुक हाउस प्रा. लि.,
महालक्ष्मी चैम्बर्स, प्रथम मंज़िल, 22, भूलाभाई देसाई रोड़, बम्बई 400 026। फोन: 4938406, 4920253.

अन्य कार्यालय:
* अहमदाबाद * पूना * हैदराबाद * कलकत्ता * चंडीगढ़
* नयी दिल्ली * बैंगलोर * त्रिवेन्द्रम * मद्रास * पटना

ARMS-IBH-65

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पार्टियों के खिलाफ वोट दिए. उन्होंने मुमताज भुट्टो, रसूल बख्श पलेजो जैसे नेताओं तथा सिंध नेशनल एलायंस को पूरी तरह नकार दिया. हाल के वर्षों में घुटने टेक देने वाले इजइ के अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जतोई या जिया के साथी, पूर्व प्रधानमंत्री मुहम्मद खां जुनेजो और उनके धार्मिक गुरु पीर पगारो जैसे नेताओं को कई प्रांतीय मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों के साथ पराजय का मुंह देखना पड़ा.

इस सूबे के दो महानगरों—कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम के नेताओं को बरसों की जद्दोजहद का मीठा फल मिला. पंजाब में आखिरी मौके पर पलड़ा बदल देने वाले पूर्व रक्षा राज्यमंत्री राणा नईम महमूद तथा अपने चुनाव क्षेत्र की सुध न लेने वाले पीपीपी के महासचिव जनरल टिक्का खां जैसे नेताओं को मुंह की खानी पड़ी. लेकिन सबसे सनसनीखेज हश्र हुआ—जिया के करीबी, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत के मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक का. सबसे अहम बात तो यह रही कि वर्षों के इस्लामीकरण के बाद धार्मिक पार्टी, जमात के कुल मिलाकर पांच उम्मीदवार ही 237 सदस्यों वाली राष्ट्रीय असेंबली में पहुंच सके.

इजइ की 54 सीटों की तुलना में 94 सीटें जीतकर पीपीपी निश्चित ही सरकार बनाने की स्थिति में है. ऐसे में राष्ट्रपति इस्हाक खां द्वारा बेनज़ीर को प्रधानमंत्री के रूप में नामांकित करने में की जा रही देरी सर्वथा अनुचित ही मानी गई. लेकिन बेनज़ीर को इंतजार की घड़ियां गिनते रहने को मजबूर कर देने की वजहें कुछ और हैं. सत्तारूढ़ इजइ के हाथ से इस्लामाबाद का तख्त तो निकल गया

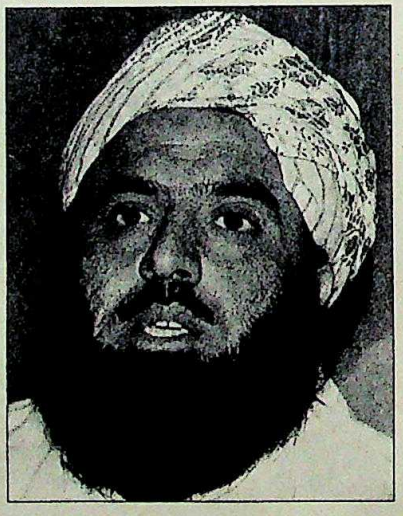

एमक्यूएम के हुसैन और जेयूआई के रहमानः साझेदारी?

लेकिन पंजाब में आस बाकी थी. इजइ ने वहां पीपीपी की 94 सीटों की तुलना में 108 सीटें हासिल की हैं और सूबे के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ को उम्मीद है कि कुछ निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से वे अपनी सरकार तो बनाए ही रख सकते हैं.

अगर बेनज़ीर प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो पंजाब में भी सरकार बनाने के मामले में पीपीपी बेहतर स्थिति में आ जाएगी. जैसा कि बेनजीर के एक सलाहकार ने कहा, "पंजाब पर नियंत्रण किए बिना पाकिस्तान पर राज नहीं किया जा सकता."

बेनज़ीर को प्रधानमंत्री बनाने में विलंब करने के और कारण भी हैं. भुट्टो की नौजवान और उत्साही बेटी एक ऐसी पार्टी की नेता की हैसियत से सत्ता के लिए दावा कर रही है जिसके संस्थापक को सेना ने सत्ता से हटाया, बाद में फांसी पर लटका दिया और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल की सजा और सैनिक दमन की भट्ठी में झोंक दिया. माना जाता है कि जिया की जगह आए नए सेनाध्यक्ष जनरल मिर्जा असलम बेग सेना को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं. फिर भी पीपीपी के सत्ता में लौटने से यह डर तो उभर ही आया है कि पार्टी कहीं भुट्टो को फांसी पर लटकाने के लिए फौज से हिसाब चुकता करने न लग जाए. बेनज़ीर ने रात गए तीन घंटे जनरल बेग से क्या गुफ्तगू की, इसका कोई खुलासा नहीं किया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने "राजनैतिक स्थिति पर बातचीत की."

फिर भी, पाकिस्तानी फौज का एक बड़ा तबका मानता है कि फौज सियासत में दखल देती रहेगी तभी पाकिस्तान एकजुट रह पाएगा. इस तबके की मंशा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के कामकाज से स्पष्ट हो जाती है. यह संगठन अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी लड़ाई चलाने के साथ ही घरेलू राजनीति पर भी नजर रखता और उसमें जोड़-तोड़ करता रहता है. अभी आईएसआई के प्रमुख हैं— मेजर जनरल हमीद गुल और मुल्क में केंद्रीय सत्ता होने के बावजूद इस संगठन की अपनी स्वंतत्र सत्ता चलती है. इसकी राजनैतिक शाखा में हजारों लोग बताए जाते हैं.

अवाम का फरमान लेकर आई पीपीपी की सरकार फौज की मौजूदा भूमिका को कम करने की कोशिश कर सकती है, खास तौर से पाकिस्तान की परमाणु नीति, अफगानिस्तान और प्रतिरक्षा बजट के मामलों में. जब चुनाव के बाद जरनल बेग ने नेताओं से "आपसी तालमेल से लोकप्रिय सरकार का गठन करने" की अपील की तो पीपीपी के बारे में उनकी बेचैनी साफ उजागर हो गई. पीपीपी और इजइ की मिली-जुली सरकार का विचार तो सिरे से ही अव्यावहारिक था. लेकिन पीपीपी को इस्हाक खां को नया राष्ट्रपति स्वीकार कर लेने के लिए राजी कर लिया गया, शायद इस ख्याल से कि 73 साल का यह पूर्व नौकरशाह नातजुर्बेकार बेनज़ीर पर कुछ न कुछ अंकुश रखने में कामयाब रहेगा.

लेकिन पीपीपी अपना नया नरम रुख छोड़कर एकाएक पुराने उग्र तेवर अख्तियार नहीं करेगी, इस बात की फौज को एक पुख्ता गारंटी है— वह यह कि राष्ट्रीय असेंबली में बेनज़ीर की पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है. बेनज़ीर को निर्दलीय सदस्यों तथा एमक्यूएम और मौलाना फज़लुर रहमान की जमायते-उलेमा-ए-इस्लाम (जेयू-आई-एफ) जैसी छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल करना ही होगा. और फिर इन छोटी पार्टियों को फौज कभी भी पीपीपी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर कर ही सकती है.

1983 में विश्वविद्यालय छात्र संगठन से निकले एमक्यूएम का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नेतृत्व 36 वर्षीय अल्ताफ हुसैन करते हैं. सगंठन ने उर्दूभाषी मुहाजिरों, पठानों और अभी हाल में सिंधियों के साथ जातीय संघर्ष में अगुआ की भूमिका निभाई है. एमक्यूएम की मांग है कि मुहाजिरों को पाकिस्तान की पांचवीं राष्ट्रीयता की मान्यता दी जाए और बांग्लादेश में फंसे बिहारी मुसलमानों को पाकिस्तान बुला लिया जाए. यह दोनों ही मांगें ऐसी हैं जो मुल्क के दूसरे जातीय तबकों के गले नहीं उतरतीं. लेकिन एमक्यूएम अपना रुख थोड़ा नरम कर दे और इस्लामाबाद तथा कराची की सरकारों में हिस्सेदार बनने को तैयार हो जाए तो वह मुहाजिरों को ज्यादा फायदा दिला सकता है.

एमक्यूएम और जेयूआई-एफ दोनों ही मंत्रिमंडल में दो कैबिनेट पद मांग रहे हैं. एमक्यूएम वित्त मंत्रालय चाहता है ताकि वह अपने लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सके. जबकि बेनज़ीर ने 42 वर्षीय रहमान को धार्मिक मामलों का मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है. लेकिन जेयूआई-एफ का रुख सार्वजनिक तौर पर बहुत स्पष्ट नहीं है. पीपीपी के खिलाफ भी उसके विरोधाभासी बयान आए हैं.

जेयूआई-एफ के विरोधाभासी रुख से साफ झलकता है कि सऊदी अरब जैसी परंपरावादी इस्लामी सरकारें पाकिस्तान की मजहबी पार्टियों और नेताओं को किस कदर प्रभावित करती हैं. ये ताकतें शायद नहीं चाहतीं कि बेनज़ीर किसी इस्लामी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएं. सऊदी अरब बेनज़ीर के प्रधानमंत्री बनने से तमाम मुसलमान औरतों पर पड़ने वाले असर से फिक्रमंद लगता है. लेकिन सऊदी अरब के दबाव के बावजूद जेयूआई-एफ के नेताओं की राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं भी तो जोर मार रही हैं.

इससे भी अहम है अमेरिका का रुख. अमेरिकियों को पाकिस्तान में पहले ही सदमा लग चुका है. हाल ही में जनरल बेग ने देश की पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के बीच रणनीतिक सहमति का प्रस्ताव रखा था. अमेरिकी अधिकारी इससे हलाकान हो उठे हैं. यह प्रस्ताव भारत के खिलाफ तो है लेकिन इससे इस क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को तगड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान पर इस महाशक्ति का असर काफी कम हो जाएगा.

फिर भी, अमेरिका पाकिस्तानी फौज के भीतर अपने लग्गू-भग्गुओं के बूते अपने रणनीतिक हितों की हिफाजत करने की जुगत भिड़ा सकता है लेकिन सियासी मोर्चे पर अब उसके सामने बहुत कम रास्ते बचे हैं. चुनाव कराने के लिए दबाव डालने के बाद अब वह लोकप्रिय सरकार बनाने का विरोध नहीं कर सकता. इसके अलावा बेनज़ीर 1986 में जब से पाकिस्तान लौटीं है तभी से बहुत सोच समझकर अमेरिका समर्थक बोली बोल रही हैं. राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद बेनज़ीर ने अमेरिकी राजदूत राबर्ट ओकले से दो बार मुलाकात की.

यह तो तय ही है कि पीपीपी के सत्तारूढ़ होने पर पाकिस्तान-भारत रिश्तों की समीक्षा की जाएगी. इजइ के भारत विरोधी प्रचार के बावजूद बेनज़ीर ने चुनाव अभियान में भारत के प्रति बहुत संयम से काम लिया है. चुनाव से पहले वे कहती रही हैं कि उनकी पार्टी भारत से शिमला समझौते के आधार पर रिश्ते बनाएगी. और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत के साथ मेल-मिलाप की कोशिश गंभीरता से करेंगी. बेनज़ीर के एक सलाहकार कहते हैं, "राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुने गए पीपीपी के अधिकांश लोग नौजवान और शिक्षित हैं. भारत के साथ अमन-चैन से रहने की अहमियत उन्हें पता है. हम जेहाद वाली बीमारी से मुक्त हैं." यह पहला मौका है कि सीमा के इस और उस पार विभाजन के बाद की पीढ़ी इन दोनों मुल्कों की नियंता बन गई है.

लेकिन भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति हौले-हौले ही बदलेगी. बेनज़ीर सबसे पहले शायद अवाम के मन से इजइ के दुष्प्रचार का असर उतारने की कोशिश करेंगी. एक राजनयिक पर्यवेक्षक कहते हैं, "इस्लामाबाद में उदार सरकार बनने से भारत के साथ रिश्ते निश्चित ही सुधरेंगे लेकिन रातोरात भारी बदलाव की उम्मीद करना अव्यावहारिक होगा." दिसंबर में इस्लामाबाद में होने वाली दक्षेस बैठक में भाग लेने के लिए अगर राजीव गांधी जाते हैं तो इससे दोनों नेताओं को रिश्ते सामान्य करने की बातचीत शुरू

अधिकांश लोग जो पीपीपी के टिकट पर चुने गए, नौजवान और शिक्षित हैं. वे भारत के साथ अमन-चैन से रहने की अहमियत जानते हैं और जेहाद वाली बीमारी से मुक्त हैं

इस्हाक खां के साथ बेनज़ीर

पंजाब में सेना के जवानः नई जिम्मेदारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने का पहला मौका मिल जाएगा.

पाकिस्तान के चुनाव से कई दूसरे दूरगामी परिवर्तनों के भी संकेत मिले हैं. राष्ट्रीय असेंबली की आगे की कतारों में बैठने वाली अकेली नौजवान नेता सिर्फ बेनज़ीर ही नहीं है, पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे वहां पहुंचे कई दूसरे नेता भी 30 से 45 वर्ष के बीच के ही हैं. चारों प्रमुख सियासी पार्टियों पीपीपी, इजइ, एमक्यूएम और जेयूआई-एफ की कमान नौजवान नेताओं के हाथ में है. पीपीपी के जिन लोगों को मंत्री बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें से कई नौजवान हैं. इनमें बेनज़ीर के वकील ऐतजाज एहसान, पूर्व नौकरशाह तारिक रहीम और फारूक लेघारी, पंजाब के नेता फजल सालेह हयात, युसुफ रज़ा गिलानी, और जहांगीर बद्र शामिल हैं.

लेकिन सत्ता की दहलीज तक पहुंची पीपीपी अपना भावी वित्तमंत्री अब भी तलाश रही है. कैंब्रिज में पढ़े जमींदार सरदार आसिफ अली कसूरी को वित्तमंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी पर वे पंजाब से चुनाव हार गए. संभावना है कि बेनज़ीर विदेश मंत्रालय अपने पास ही रखेंगी. उम्मीद है कि नौकरशाहों और आर्थिक सलाहकारों की नौजवान टीम इस्लामाबाद में अहमियत हासिल कर लेगी.

आशा यह भी है कि बेनज़ीर के प्रधानमंत्री रहते पार्टी की नीतियां व्यापारियों के पक्ष में रहेंगी. पीपीपी कोशिश करेगी कि बहुराष्ट्रीय

बेनज़ीर भुट्टो

दमन की आंच में निखरा कुंदन

बड़ी-बड़ी सपनीली आंखें पल भर में उनके दिलोदिमाग का हाल बयां कर देती हैं. कभी तो नयन आग उगलने लगते हैं, कभी नारी सुलभ कोमलता से लजाकर झुक जाते हैं. ऐसा ही बदलाव शायद बेनज़ीर के पूरे व्यक्तित्व में भी हुआ है—चमक-दमक और पश्चिमी रंग-ढंग वाली लड़की का नया ही रूप निखर आया है, परिपक्व राजनेत्री का, मुल्क की भावी मल्लिका का.

कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ पर महानता थोपी जाती है. बेनज़ीर के मामले में ये तीनों ही तथ्य इस कदर गुंथे हुए हैं कि उनका व्यक्तित्व अंतरविरोधों का संगम बनकर उभरा है. लेकिन उनकी महानता यह है कि उन्होंने अपने अतीत और पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाते हुए अपने को उस पद के काबिल साबित किया जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक नहीं की जा रही थी. उनकी सफलता का रहस्य शायद यही है कि इतिहास और उसके निर्माण में अपनी भूमिका का उन्हें बेहतर बोध रहा है. जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी होने का फायदा उन्हें चाहे जो मिला हो, यह तथ्य उनके व्यक्तित्व को उभरने देने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भी बन गया था. वे सत्ता सुख भोगने वाले समृद्ध और रसूख वाले परिवार में पैदा हुईं, कान्वेंट, रेडक्लिफ और फिर ऑक्सफोर्ड जैसी कुलीनों की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ीं और उसी माहौल में रहने के कारण पाकिस्तान की झंझावाती सियासत से दूर रहीं.

इसके बावजूद उनकी अस्मिता बरकरार रही. नतीजतन उनकी शख्सियत औरों से कुछ अलग किस्म की बनी रही. यही वजह थी कि वालिद भुट्टो ने अपनी बेगम नुसरत और दो बेटों पर तरजीह देकर बेनज़ीर को अपने सियासी वारिस के बतौर आगे बढ़ाया.

जिया के रूप में बदकिस्मती का दौर शुरू होने से काफी पहले इस्लामाबाद की गद्दी की दावेदार के रूप में बेनज़ीर धीरे-धीरे पर मजबूत इरादों से आगे बढ़ने लगी थीं. 1977 में जिया ने सत्ता पर कब्जा करके उनके वालिद को फांसी पर चढ़वा दिया. तब बेनज़ीर को अपने जीवन और महत्वाकांक्षाओं को नए तरह से संयोजित करना पड़ा, हालांकि शुरू में इस्लामाबाद का तख्त मिलना सपना नजर आता था. लगता है बेनज़ीर ने अपने पिता के दो सबसे प्रमुख गुण पाए हैं: दबंगपन और उद्दंडता. इसके साथ ही उनकी राजनैतिक अपरिपक्वता से भी पाकिस्तान में सत्ता में आने की उनकी संभावनाएं धूमिल हुई थीं.

यह बात कुछ अजीब लग सकती है पर असलियत यही है कि उनकी विश्वसनीयता बनाने और उनके उद्देश्य को सार्थक करने में सबसे बड़ी भूमिका जनरल जिया की रही. पिता की मौत के बाद निरंतर सात वर्षों तक बेनज़ीर का व्यक्तित्व दमन की आंच में कुंदन होता रहा. जेल, नजरबंदी, एकांतवास और निष्कासन की कार्रवाइयां उनके व्यक्तित्व को दबाने और उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए की गईं. लेकिन सात-साल बाद नई ऊर्जा से भरी, बलिदानी के आभामंडल से युक्त बेनज़ीर नेता के रूप में उभर आईं.

दमन की भट्टी से गुजरा उनका व्यक्तित्व सियासी मोर्चे पर अचूक और मारक अस्त्र के रूप में छा गया. अप्रैल 1986 में विजय-रथ पर सवार होकर लाहौर की सड़कों पर लौटीं बेनजीर पूरी तरह बदल चुकी थीं. बदले की आग में जलने वाली और अपने मुल्क में जिल्लत-जलालत बर्दाश्त न कर पाने के कारण परदेस में जाकर बसने वाली नौजवान लड़की का तजुर्बेकार और धैर्यवान राजनेता के रूप में रूपांतरण हो गया था.

वापसी पर अवाम ने उन्हें हाथोहाथ लिया, उनकी हौसला-अफजाई की. लोकप्रियता की चरम अवस्था में जुल्फिकार अली भुट्टो के पीछे भी इतने लोग दीवाने नहीं हुए थे. लेकिन इससे बेनज़ीर अपनी ताकत का गलत अंदाज भी लगा बैठीं. उन्होंने तब घोषणा की थी, "मैं जिस दिन चाहूं, सरकार का तख्ता पलट सकती हूं." लेकिन बेनजीर को यह समझते देर नहीं लगी कि उन्हें सिर्फ भीड़ का समर्थन ही प्राप्त है और ये लोग सेना से दो-दो हाथ करने के लिए उनके साथ सड़कों पर नहीं उतर आएंगे. उन्होंने महसूस कर लिया कि उन्हें मुल्क की व्यवस्था की जटिलताओं के भीतर ही काम करने की कुव्वत दिखानी पड़ेगी.

यही वह वक्त था जब बेनज़ीर के व्यक्तित्व का माकूल विकास हुआ. एक धनी जमींदार से उनकी शादी मुल्क के साथ उनके जुड़ाव का प्रतीक तो थी ही, इससे उनके पिछले जीवन से नाता तोड़ने का संकेत भी मिला. जिया की मौत के बाद उन्होंने जो घोषणाएं कीं उनसे उनमें आई समझदारी झलकती है. उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि फौज का दिल जीतना ही होगा. इसीलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से फौज को यह भरोसा देने वाले बयान जारी किए कि अगर उनकी सरकार बनी तो फौज का खास दर्जा बहाल रहेगा. हां, उसकी भूमिका उतनी राजनैतिक नहीं होगी. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका से पाकिस्तान के खास ताल्लुकात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कंपनियां और विदेशों में बसे पाकिस्तानी मुल्क में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश करें.

हां, पीपीपी की सरकार औरतों के उन हकों को जरूर बहाल करेगी जो जिया ने छीन लिए थे. जहां तक 1973 के संविधान को लागू करने जैसे बुनियादी बदलावों का सवाल है, सदन में दो-तिहाई बहुमत न होने के कारण सरकार के हाथ बंधे रहेंगे. इसी वजह से पीपीपी के कई नेताओं को लगता है कि बेनज़ीर को 1990 के आखिर तक मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अपना मनमाफिक सियासी संगठन बनाने के लिए उसमें काफी उलटफेर भी किए. उनके वालिद के जमाने के लोगों की जगह ऐसे नए लोग लाए गए जो उनके नजरिये और सोच से सहमत थे.

लेकिन बेनज़ीर के व्यक्तित्व में असली निखार तो चुनाव अभियान के दौरान आया. सम्मोहित करने वाली वक्ता होने के बावजूद बेनज़ीर ने एकदम नपे-तुले और संयमित भाषण दिए. तनाव भरे चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने जिया को लताड़ने की अपनी अंदरूनी इच्छा पर काबू रखा. उन्होंने महज जिया के राज की आलोचना ही की, उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई आक्षेप नहीं किया. पाकिस्तान के परंपरावादी समाज को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने यह समझदारी दिखाई.

अब, जबकि वे किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे नौजवान अगुआ बनने की राह पर हैं, उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वे फौजी राज में दबे-कुचले अपने मुल्क को बदलाव और नई उम्मीदों के खुशनुमा दौर में पहला कदम उठाने को प्रेरित करें. उन्हें सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है. लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दुनिया भर के लोगों के मन में कई आशाएं जगा दी हैं. पिछले कुछ हफ्तों में ही उन्होंने दिखा दिया है कि असरदार और जम्हूरी लीडर बनने का माद्दा और मुकम्मल लचीलापन उनमें इफरात से है.

ये उम्मीदें जल्दी मुरझा भी सकती हैं. हो सकता है बेनज़ीर फिलीपींस की कोरी एक्विनो या राजीव गांधी की तरह ही साबित हों. तवारीख में अपनी माकूल जगह बनाने के लिए उन्होंने जोरदार संघर्ष करने के साथ-साथ बहुत सारी कुर्बानियां भी दीं. और अब उनका भविष्य खुद उनके हाथ में है.

—दिलीप बॉब

उनकी शख्सियत औरों से कुछ अलग बनी रही. यही वजह थी कि वालिद भुट्टो ने बेगम नुसरत और दो बेटों पर तरजीह देकर बेनज़ीर को अपने सियासी वारिस के बतौर आगे बढ़ाया

आज बेनज़ीर अवाम की उम्मीद और उत्साह का केंद्रबिंदु बनी हुई हैं. लोग साफ देख रहे हैं कि सत्ता पीपीपी के चरण चूमने जा रही है. लेकिन बेनज़ीर कैसा नेतृत्व देती हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. काफी दारोमदार इस तथ्य पर भी होगा कि फौज उनकी सरकार को शुरू में कितना और कैसा समर्थन देती है. लेकिन चाहे जो हो एक बात तो पूनम के चांद की तरह साफ दिखाई दे रही है कि भुट्टो की बेटी ने सुनहरी रोशनाई से तवारीख में अपना नाम दर्ज करा दिया है.

—एम. रहमान, पाकिस्तान में

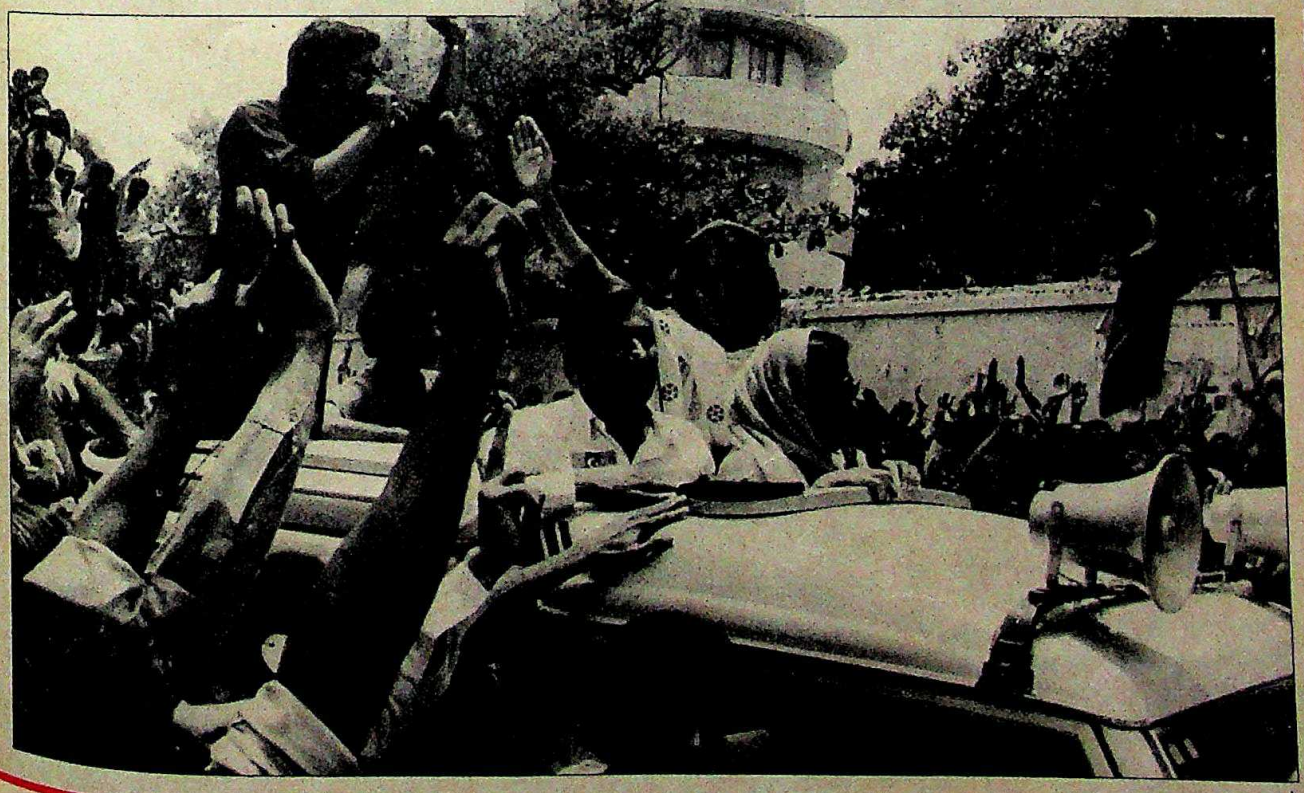

अपने घर के बाहर बेनज़ीर: नई परिपक्वता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विपक्ष

अंजाम से दूर अफसाना

एक होने को जुटे विपक्षी दल इसे खूबसूरत मोड़ भी न दे सके

"उनकी राजनीति हर रोज बदलती है: 100 घंटे बाद विपक्ष दूसरी बोली बोलने लगता है."—**लाल किले की रैली में राजीव गांधी**

विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री की यह बात सही साबित करने पर तुली दिखीं. पिछले पखवाड़े जनता पार्टी और लोकदल की जनता दल में विलय की प्रक्रिया शुरू होते ही विपक्ष के नए गठजोड़ की पहचान के बारे में उलझाव ज्यादा गहरा गया. नई पार्टी की औपचारिक घोषणा के बदले विभिन्न गुटों के नेता अपनी-अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए जूझ रहे थे. यह विरोधाभास उस समय और तीखा हो गया जब नई दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर जनता पार्टी के विशाल मुख्यालय में परस्पर विरोधी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दो झंडे फहराकर दो नामपट भी लटका दिए.

गुटों के इन झगड़ों के बुलंदी पर पहुंचने के साथ ही सभी पार्टियों के विलय के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 15 नवंबर भी चुपचाप बीत गई. और जनता दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने एक बार फिर यह साफ हो गया कि इंका का भरोसेमंद राष्ट्रीय विकल्प बनाने का वादा पूरा करने से पहले उन्हें कई बाधाएं पार करनी होंगी.

हरियाणा की पार्टी पर तो देवीलाल का सिक्का चलता ही है. उसे छोड़कर एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां नई पार्टी को लेकर विवाद न हुआ हो. चुनाव आयोग से नई पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध करने के बजाय जनता पार्टी के एक असंतुष्ट गुट ने उसे इसके उलट चिट्ठी लिख डाली.

यह संकट जनता पार्टी तक ही सीमित नहीं रहा. लोकदल भी दो धड़ों में बंट गया. पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हेमवतीनंदन बहुगुणा को अध्यक्ष पद से 'हटाकर' हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल को समर्थन दिया. देवीलाल धड़े ने तो खुद को जनता दल का अंग घोषित कर दिया पर बहुगुणा ने फिलहाल इससे बाहर ही रहने का फैसला किया.

अक्तूबर में बंगलूर में हुए स्थापना सम्मेलन से विपक्षी एकता को मिले बल के बाद राष्ट्रीय विपक्ष फिर टूटता नजर आने लगा. सम्मेलन के तुरंत बाद झंझट शुरू हो गया. वी.पी. सिंह ने लोकदल और जनता पार्टी पर दबाव डाला कि वे विलय की पुष्टि के लिए अपनी राष्ट्रीय समितियों की बैठक बुलाएं. बहुगुणा विलय के विरोधी थे ही, इसलिए उन्होंने बैठक बुलाने से इनकार कर दिया. इससे जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी अपनी बैठक स्थगित करवाने का बहाना मिला. वे विलय स्थगित कराना चाहते थे.

एकता का अपना सपना भंग होते देख देवीलाल हरकत में आ गए. उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर, लोकदल को भंग करने और जनता दल में उसके विलय के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करवाकर गेंद बहुगुणा के पाले में डाल दी. बहुगुणा और उनके मुट्ठी भर समर्थकों ने सम्मेलन का बहिष्कार किया. देवीलाल ने घोषणा की, "अब यह साफ हो गया है कि विपक्षी एकता के दुश्मन कौन हैं. वे लोग सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर सम्मेलन में नहीं आए."

पीटीआई

चार घंटे के घमासान के बाद ही जपा राष्ट्रीय परिषद आखिर जैसा-तैसा प्रस्ताव पास कर पाई

जपा बैठक में (बाएं से) चंद्रशेखर, अजीत, दंडवते: नोकझोंक

बहुगुणा भी भिड़ने की मुद्रा में थे. उन्होंने कहा, "देवीलाल ने आज की राजनीति को अपने व्यक्तित्व से जोड़ लिया है. उनके पास न तो कोई मुद्दा है, न विचारधारा. वे न कोई बहस चलने देना चाहते हैं और न ही जनता की वास्तविक आकांक्षाओं को समझते हैं. ये लोग देश की राजनीति में बांझपन और शून्यता का माहौल पैदा कर रहे हैं."

जहां लोकदल में तर्क-वितर्क होते रहे, वहीं जनता पार्टी में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई. पार्टी की राष्ट्रीय समिति के सदस्य 18 नवंबर की बैठक से पहले ही विलय समर्थक और विलय विरोधी गुटों में बंट गए थे. विलय विरोधी धड़े की कमान सुब्रमण्यम स्वामी, सैयद शहाबुद्दीन और यशवंत सिंहा (सभी सांसद) सरीखे लोगों के हाथ में थी, जिन्हें नई पार्टी में कोई पद मिलने की उम्मीद नहीं है. उधर, विलय समर्थक गुट की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अगुआई मधु दंडवते और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े कर रहे थे.

जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर के विलय प्रस्ताव रखते ही धमाचौकड़ी मच गई. विभिन्न धड़ों के नेताओं के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई. चंद्रशेखर और दंडवते दोनों को ही मंच से उतरकर कार्यकर्ताओं को शांत करना पड़ा. यहां तक कि मंच पर लगा दिवंगत चरण सिंह का चित्र भी गरमागरम बहस का मुद्दा बन गया. चित्र वहां लगा रहे या नहीं, इस पर तकरार होने लगी. बैठक की अध्यक्षता अजीत सिंह कर रहे थे, इसलिए उनके विरोधियों ने चुनौती दी कि जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव सरीखी विभूतियों की अनदेखी की गई है. तंग आकर चंद्रशेखर ने इसमें सुधार करने की पेशकश की. समस्या सुलटने के बजाय सम्मेलन से द्वेष ही बढ़ा. चार घंटे के घमासान के बाद ही राष्ट्रीय परिषद आखिर एक जैसा-तैसा प्रस्ताव पास करने में सफल हो पाई.

विरोधी किसी भी तरह विलय का समर्थन करने के मूड में नहीं थे. यहां तक कि इंदूभाई पटेल और दिल्ली जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेश प्रताप चौधरी सरीखे वरिष्ठ नेताओं ने हेगड़े के समर्थकों को पार्टी मुख्यालय में नए जनता दल का नामपट लगाने से भी रोका. उदास दिख रहे दंडवते ने बाद में टालने के अंदाज में कहा, "राजनैतिक पार्टियों का विलय कंपनियों की तरह नहीं हो सकता. इनमें हमेशा कुछ-न-कुछ खामी रह जाती है जिसे बाद में दूर कर लिया जाता है. 1977 में जनता पार्टी के गठन के दौरान भी सारी औपचारिकताएं आखिर चुनावों के बाद ही तो पूरी की जा सकी थीं."

मानो इतना ही काफी नहीं था. चंद्रशेखर समर्थक नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह को लिखा कि जब तक पार्टी भंग नहीं हो जाती और इससे संबंधित मुद्दे तय नहीं हो जाते, विलय नहीं हो सकता. स्वामी ने कहा, "गाड़ी को घोड़े के आगे नहीं बांधा जा सकता. बंगलूर में यह तय हुआ था कि विलय से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी. मकान बनने से पहले हम उसका पूरा नक्शा चाहते हैं."

यह साफ था कि विलय के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले स्वामी और दूसरे लोग अकेले नहीं हैं. वी.पी. सिंह के करीबी सूत्रों का आरोप है कि चंद्रशेखर भी परदे के पीछे से बाधाएं खड़ी कर रहे हैं. ताकि जनता दल नेतृत्व पर उन्हें महत्वपूर्ण पद देने के लिए दबाव पड़े. इसी के मुताबिक चंद्रशेखर के समर्थक शहाबुद्दीन ने अजीत सिंह को एक पत्र लिखकर मांग की कि:

- विलय के पहले जनता पार्टी के संविधान में संशोधन किया जाए और पार्टी के प्राथमिक और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया जाए.
- विलय के पहले जनता दल की जिला और राज्यस्तरीय इकाइयों के गठन के साथ संसद में जनता दल और राज्यों में विधायक दलों के नेताओं की घोषणा की जाए.
- जनता पार्टी के अधिवेशन में अजीत सिंह जनता दल के पदाधिकारियों की तदर्थ पैनलों की घोषणा करें.

चिट्ठी ऐसे महत्वपूर्ण समय पर जारी की गई जब वी.पी. सिंह सम्मेलन के तुरंत बाद जनता दल की कार्यकारिणी की घोषणा करने वाले थे. स्पष्ट है कि चंद्रशेखर गुट की कोशिश थी कि नई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तदर्थ पैनल में अधिक से अधिक अपने आदमी रखवाए जाएं.

इन सब चालबाजियों से विपक्ष के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल गिर गया. जपा महासचिव हरिकेश बहादुर ने खेद जताया, "हम बड़े उद्देश्यों के लिए अपने छोटे हितों को भी कुर्बान करने में असमर्थ हैं."

लेकिन वी.पी. सिंह और देवीलाल दोनों ही इस सबसे अविचलित रहे. जहां वी.पी. सिंह ने देश का दौरा करने, जनसभाएं करने और 'महत्वपूर्ण लोगों' से सलाह-मशविरा करने का फैसला किया, वहीं देवीलाल ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुगुणा के समर्थकों को अपने गुट में मिला लिया. इससे बहुगुणा गुट को बहुत धक्का पहुंचा.

वी.पी. सिंह और देवीलाल ने 'कभी न हिम्मत हारने की भावना' से काम लेते हुए जनता दल के पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए चंद्रशेखर और दूसरे लोगों से भी बातचीत शुरू की. वी.पी. सिंह ने घोषणा की, "मैं तो पैदाइशी आशावादी हूं. लोग एकता चाहते हैं और यह होकर रहेगी." उन्होंने यह भविष्यवाणी करने का जोखिम मोल नहीं लिया कि एकता कब तक होगी. पर वे रोजाना यह दुआ करते ही होंगे कि लोगों द्वारा विपक्ष के नकार देने से पहले ही एका हो जाए. लोग विपक्ष की बेतुकी नटबाजी से वैसे भी ऊबे और चिढ़े बैठे हैं.

—प्रभु चावला और पंकज पचौरी

देवीलाल धड़े ने बहुगुणा को अध्यक्ष पद से 'हटाकर' खुद को जनता दल का अंग घोषित किया

प्रमोद पुष्करणा

लोकदल सम्मेलन में देवीलाल (बीच में): ठोस रवैया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूँ.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृपया भुगतान लिबिंग मीडिया इंडिया लि० के नाम पर बनाए.

Walt Disney
डिस्नी टुडे

अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO. USA.

MILESTONES/DT/114 Hin a

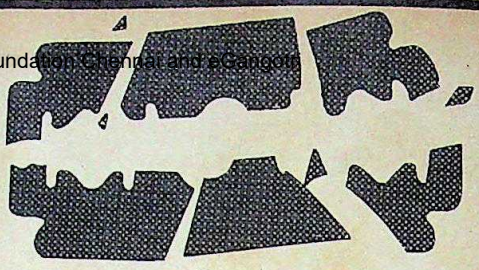

पुरानी आदत बदल डालो

दोहरा लाभ उठालो

पुराने ज़माने के रेज़र ब्लेड से विदा लो.

और अपनालो विल्मन II. सुघड़, सलोना, आधुनिकतम ट्विन-ब्लेड शेविंग सिस्टम. साफ-सुथरी, चिकनी, बेहतर शेव बनाये.

विल्मन II का काम बिल्कुल निराला. परिपूर्ण शेव के लिए कार्ट्रिज में वैज्ञानिक तरीके से नपे-तुले कोण पर दो ब्लेड फिट होते हैं. पहला ब्लेड बाल को खड़ा करके अधिकांश को काट देता है. साथ ही साथ दूसरा ब्लेड बाल को त्वचा तक बिल्कुल साफ कर देता है.

मतलब अगर एक से कुछ छूटे तो दूसरे से कुछ न छूटे!

यह है दोहरा लाभ!
तभी तो रवि शास्त्री इस्तेमाल करते हैं विल्मन II. ट्विन-ब्लेड सिस्टम. विल्किनसन टेक्नॉलॉजी की श्रेष्ठतम रचना.

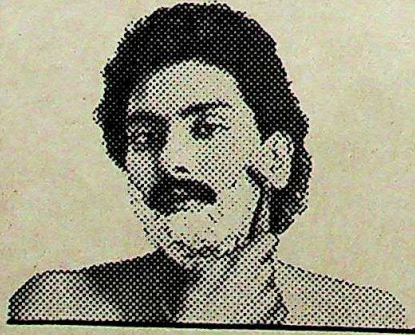

WILTECH
Leaders in quality
Leaders in twin-blades

अपनाइये

विल्मन II

वर्ल्ड क्लास ट्विन-ब्लेड

शेव के गुर जानने के लिए मुफ्त पुस्तिका हेतु विल्टेक इन्डिया लिमिटेड, एम जी रोड, बेंगलोर-560 001 को लिखें.

HTA 8877

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार

चोले की फिक्र

जमात-ए-इस्लामी के नए तेवर

"मुल्क के मसलों पर बेरुखी दिखाने के बजाय उनमें गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए और हालात को सुधारने की भरसक कोशिश करनी चाहिए."

—मौलाना अबुल लईस इस्लाही नदवी, अमीर, जमात-ए-इस्लामी हिंद ; 5 नवंबर '88

जमात-ए-इस्लामी की धार्मिक विचारधारा से वाकिफ लोगों को इस बयान से लग सकता है कि यह संगठन धर्म-त्याग कर रहा हो मगर सच तो यह है कि यह संगठन हमेशा से— और भारत की स्वतंत्रता से कहीं पहले से— भारत में हुकूमत-ए-इलाहिया (खुदा का राज) कायम करने के ख्वाब देखता रहा है. नदवी ने एक बार यहां तक कहा था कि धर्मनिरपेक्ष संगठनों से सहयोग करना 'हराम' है.

इसलिए नदवी के इस नए रुख से ही नहीं, जमात के देशव्यापी 'नफरत मिटाओ, इंसानियत बचाओ' आंदोलन से भी हर कोई हैरान-सा है. जमात के कट्टरपंथी रवैये में परिवर्तन को सरकारी और राजनैतिक हलकों में भी महसूस किया गया है. मसलन बिहार के अनेक जिलों में जमात के नेताओं ने संवेदनशील सांप्रदायिक मसलों पर गैर-मुस्लिम बुद्धिजीवियों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया. मुंगेर में उन्हें अपना जलसा एक धर्मशाला में करने दिया गया और रांची में उनकी एक गोष्ठी का उद्घाटन उपायुक्त सज्जल कुमार चक्रवर्ती ने किया. बिहार में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात की सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा देने वाले सांसद जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें एक खत भेजा जिसमें उनकी नई भूमिका की तारीफ की गई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशें दरअसल 'वक्त की मांग' हैं.

इसी तरह के आयोजन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी किए गए. जमात के प्रवक्ता शफी मूनीस का कहना है, "यह सब सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है."

लेकिन दांव पर इससे कहीं ज्यादा अहम मुद्दे लगे हैं. यह बात समझ में नहीं आती कि कोई कट्टरपंथी संगठन रातोरात बिना किसी प्रेरणा या फायदे के सांप्रदायिक सौहार्द की बातें कैसे कर सकता है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जमात के रुख में यह बदलाव यथार्थवादी सोच का नतीजा है. तमाम कोशिशों के बावजूद यह संगठन राजनैतिक साख बनाने में नाकाम रहा है. अब जबकि चुनाव साल भर बाद ही होने वाले हैं और मुस्लिम मतदाताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है, जमात के नेताओं को लगता है कि वे लचीला और राजनैतिक रुख अपनाकर और हुकूमत-ए-इलाहिया के ख्वाब के बजाय 'मानवीय' मुद्दे को उछालकर मुसलमान समुदाय में संगठन की साख बढ़ा सकते हैं.

एक वक्त था कि जमात के सदस्यों को वोट देने की भी इजाजत नहीं थी. लेकिन युवा कार्यकर्ता संगठन पर हावी रूढ़िवादी मान्यताओं से किनाराकशी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं. कट्टरपंथी तत्वों के दबाव के बावजूद जमात ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा उदार रवैया अख्तियार किया है.

जैसा कि नदवी बताते हैं, "सैद्धांतिक रूप से जमात केवल चुनावों में सीधी भागीदारी के खिलाफ है. चुनाव में यह अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहती क्योंकि अभी हालात माकूल नहीं हैं." जमात के सचिव मौलाना सिराजुल हसन कहते हैं, "वर्तमान नीति के तहत जमात अपने सदस्यों को चुनींदा उम्मीदवारों को वोट देने की इजाजत देगी और किसी भी मुस्लिम विरोधी दल की तरफदारी नहीं करेगी."

अपनी इस नई भूमिका के पहले जमात की भूमिका कुल मिलाकर मुसलमानों की 'पहचान' पर किसी भी संभावित खतरे का पुरजोर मुकाबला करने की रही है. शाह-बानो प्रसंग पर फैसले के बाद जमात ने 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' के गठन में मदद की, और बाद में अपना हाथ खींच लिया. अपनी नई छवि को प्रचारित करने के लिए इसने हिंदू धर्म और इस्लाम पर हिंदी और उर्दू में किताबें प्रकाशित करनी शुरू कर दी हैं. लेकिन राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपनी संयमित भूमिका के कारण जमात की नई साख बनी है. जमात के महासचिव अफजल हुसैन बाबरी मस्जिद समन्वय समिति के सदस्य भी हैं. इस समिति के संयोजक सैयद शहाबुद्दीन हैं. जमात के नेता खुलेआम दावा करते हैं कि मसले को सड़कों पर ले जाने की समिति की कोशिशों को उन्होंने ही नाकाम किया है. समिति के अयोध्या मार्च के आह्वानों को जमात ने यह कहते हुए नाकाम करवा दिया कि जन आंदोलन गैर-इस्लामी बात है. मौलाना नदवी ने तो यहां तक कहा कि यदि हिंदू यह साबित कर दें कि विवादास्पद जगह राम की जन्मभूमि थी तो मुसलमान उस पवित्र स्थल को उनके सुपुर्द कर देंगे.

जमात के नेता कहते हैं कि संगठन के स्वरूप में योजनाबद्ध तरीके से फेरबदल नए

हसन के साथ नदवी (दाएं)

कृष्ण मुरारी किशन

जमात ने सांप्रदायिक जामे को उतारने की कोशिश चुनावी प्रक्रिया पर अपनी पकड़ बनाने के लिए की है, जिसमें पहले उसे भाग भी लेने नहीं दिया जा रहा था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सदस्यों को आकर्षित करने के लिए किए गए हैं. इसके कट्टर रुख की वजह से इसके आलोचकों को इसे महज एक सांप्रदायिक संगठन करार देने का मौका मिला है, और जमात में एक तरह का ठहराव आ गया. मुसलमान समुदाय के अगुआ लोगों और बुद्धिजीवियों को अपने साथ लेने के बावजूद इसके नेता स्वीकार करते हैं कि जमात ने समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हितों की अनदेखी की है. एक प्रवक्ता का कहना है, "अब हमारी अपील जनता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए. हमें दूसरों को भी भरोसा दिलाना होगा कि वे हमें महज एक फिरकापरस्त गुट न मानें."

जमात की इस रणनीति के पीछे कुछ हद तक इस सरकारी घोषणा का भी हाथ रहा है कि वह चुनावों में सांप्रदायिक संगठनों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है. जमात का मकसद कुछ भी हो, लेकिन ज्यादातर भारतीय अभी भी जमात को एक ऐसे 'सांप्रदायिक' संगठन के रूप में देखते हैं जो लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करना और इस्लाम को स्थापित करना चाहता है. जमात के नेताओं को इस बात का एहसास है कि इस छवि को बदलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. लेकिन क्या कट्टरपंथी तत्व इस संगठन पर फिर हावी नहीं हो जाएंगे? यह सवाल अभी भी कायम है. वैसे फिलहाल जमात की बागडोर युवा तुर्कों के हाथ ही है और उनका पक्का मानना है कि 'नफरत मिटाओ, इंसानियत बचाओ' आंदोलन सही दिशा में एक सही कदम है.

—फरजंद अहमद

बिहार

तबादलों का तांता

अफसरशाही में असंतोष

"मैं तबादले का धंधा बंद करवाऊंगा... मैं काम करने की नई संस्कृति कायम करना चाहता हूं."

समस्याग्रस्त बिहार के तख्त पर विराजते समय भागवत झा आजाद के मुख से ऐसे ही फूल झरे थे. पर अब ये फूल मुरझा गए लगते हैं. राज्य की नौकरशाही की मुश्कें कसने का उनका अरमान अधूरा ही रह गया. इसके बजाय नौ महीने के उनके शासन में नौकरशाही की हालत और बिगड़ गई है. आजाद के अड़ियल रवैये के मद्देनजर इसकी वजह भी विडंबनात्मक है. एक वरिष्ठ अफसर के ही मुताबिक मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अरुण पाठक की जोड़ी लगातार बेमतलब तबादले और नियुक्तियां कर रही है.

पिछले पखवाड़े राज्य सचिवालय में उस समय संकट खड़ा हो गया जब शिक्षा आयुक्त आर.एस. तिवारी ने उत्पाद आयुक्त के पद पर अचानक किए गए अपने तबादले को चुनौती देते हुए कार्यभार सौंपने से इनकार कर दिया. यही नहीं, तिवारी की जगह भेजे गए ए.यू. शर्मा भी विरोधस्वरूप छुट्टी पर चले गए और उत्पाद आयुक्त जे.एल. आर्य अभी छुट्टी से लौटे नहीं थे. पर कार्मिक सचिव एम.एल. मजूमदार ने गुस्से में आकर तिवारी को चिट्ठी भेज दी कि अगर वे तत्काल कार्यभार नही सौंपते तो उन्हें कार्यमुक्त समझा जाएगा. तिवारी के सहकर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार ने संबंधित मंत्री की सलाह के बिना ही

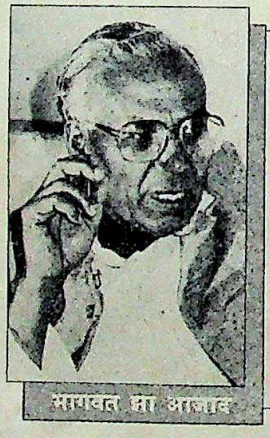

भागवत झा आजाद

वरिष्ठ अफसर आस्तीनें चढ़ा कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की मंडली द्वारा किए गए तबादलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं

अरुण पाठक

आयुक्त स्तर के अफसर का तबादला करके परंपराओं को तोड़ा है. पर पाठक कहते हैं, "सब कुछ सामान्य है."

नौकरशाही में फेरबदल होना पाठक के लिए कोई अनजानी बात नहीं है. वे खुद भी 22 आईएएस अफसरों की वरिष्ठता लांघकर मुख्य सचिव बने थे. राज्य में आईएएस अफसरों के साथ ही आईपीएस अफसरों के हौसले भी पस्त हैं. वे कुछ महीने पहले जे.एम. कुरेशी को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने से खासतौर पर नाराज हैं क्योंकि कुरेशी बिहार कैडर के नहीं हैं.

वरिष्ठ अफसरों को बोरिया-बिस्तर समेटने के बेमतलब आदेश देने वाले राजनैतिक दलालों की कमर तोड़ने के बजाय आजाद तुष्टीकरण की नीति पर चलते आए हैं. उन्होंने आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर के छह-छह नए पद बना दिए. वे कहते हैं, "मैंने नियमों पर अमल करने की पूरी कोशिश की. लेकिन कुछ तबादले प्रशासनिक कारणों से करने ही पडते हैं." पर सचाई यह है कि तबादलों का अधिकार फिर से मंत्रिमंडल को दे पाने में वे नाकाम रहे हैं. हालांकि उनके पूर्ववर्ती बिंदेश्वरी दुबे ने यह अधिकार अपने नजदीकी अफसरों को सौंप रखा था.

नतीजतन, तबादले बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे हैं. कुछ बानगियां देखें:

- बी.बी. लाल सिर्फ दो महीने के लिए राजस्व आयुक्त बनाए गए. इसके बाद उन्हें संबंधित मंत्री की जानकारी के बिना ही पर्यटन आयुक्त बना दिया गया.
- एस.एन.पी.एन. सिन्हा कभी बिहार राज्य मंल व्ययन बोर्ड में थे. तब से वे उत्पाद आयुक्त, नगर विकास आयुक्त, खनन आयुक्त और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में भी रह चुके हैं.
- छह महीनों के भीतर ही सरकार ने मगध क्षेत्र में पांच आयुक्त तैनात किए. पर कोई भी ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ.

और भी कई अनियमितताएं हैं. कनिष्ठ अफसरों को अक्सर बड़े जिलों में भेज दिया जाता है जबकि वरिष्ठ अफसरों को छोटे जिलों का कार्यभार दिया जाता है. जातीय तत्व की भी भूमिका रहती है. राज्य के 39 जिलों में से 31 के कलक्टर या तो ब्राह्मण हैं या कायस्थ. हद तो यह है कि पांच अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त के यहां दर्ज होने के बावजूद उन्हें कलक्टर बनाया गया.

आजाद नौकरशाहों से भी पार्टीजनों सरीखा बरताव ही करते हैं. उनमें भी असंतुष्टों का एक बड़ा गुट तैयार हो गया है. जब तक बिहार के अफसरों से मनमानी की जाती रहेगी, अव्यवस्थित बिहार को व्यवस्थित करने का आजाद का दावा खोखला ही रहेगा.

—फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हीरो होन्डा के सवार को आप रोक न पायेंगे.

दिल की बात कहने से.

1985 में जब हमने हीरो होन्डा सी डी 100 पहली बार पेश की तो हमें पूरा विश्वास था कि यह एक अच्छी मोटरसाइकिल है। इस बात की पुष्टि हीरो होन्डा के सभी मालिक करते हैं। कुछ लोग इसकी किफ़ायत पर (1 लीटर में 80 कि.मी.*), तो कई इसकी आसान देखभाल पर फ़िदा हैं। और अन्य, होन्डा नाम पर। सभी 4-स्ट्रोक वाली भारत की एकमात्र 100 सी.सी. मोटरसाइकिल चलाने में गज़ब का आनन्द पाते हैं। होन्डा इन्जिनियरिंग – हीरो का चुनाव। नतीजा – हीरो होन्डा अपनाने वाले 2,00,000 सन्तुष्ट खरीदार। तभी तो हम आप सबकी बेकीमत कह सकते हैं यही है आपका शानदार हमसफ़र।

देखा आपने, सब की एक राय...

आपका शानदार हमसफ़र!

HERO HONDA

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्र. क्या बाहर बहुत ठंड है ?

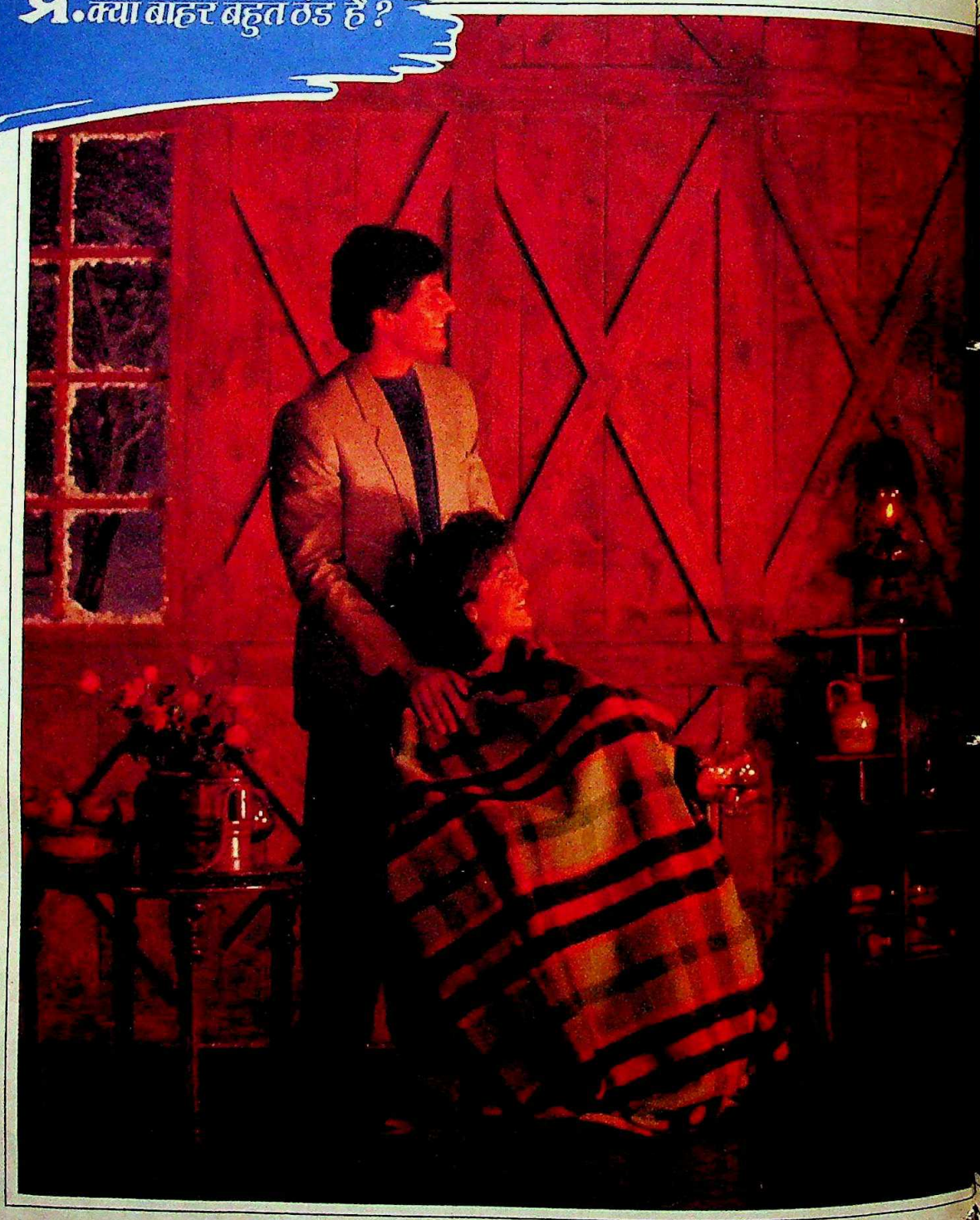

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रे म ण्ड के ब्लै न्के ट

उ. नहीं, यह तो गर्मी से बचने के लिए है!

रेमण्ड

सर्वांगीण सर्वोत्तम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऑल्विन प्रतीक्षा करने लायक क्यों है?

ऑ **ल्विन की अपनी अलग श्रेणी है**
किसी भी समय, ऑल्विन के लिए प्रतीक्षा सूची होती है। और ऐसे लोग भी, जो अपना ऑल्विन प्राप्त करने के लिए खुशी से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि ऑल्विन रेफ्रिजरेटर की अपनी अलग श्रेणी है। यह सविशेष शांत निष्पादक अतुलनीय लक्षणों के साथ, वर्षों तक बिना तकलीफ सेवा देने के लिए बना है। आप खुद जाँच करके देख लें।

हि **ताची निर्मित कॉम्प्रेसर**
शांत, अस्खलित और बिना तकलीफ कार्यक्षमता के लिए।

वो **ल्टेज स्टेबिलाइसर की आवश्यकता नहीं**
क्योंकि वह १७० से २५० वोल्ट तक बिजली के उतार चढ़ाव को अपने में समा लेने के लिए बना है।

रो **ल बॉन्ड फ्रीज़र**
शीघ्र गति से बनते बर्फ, ताजी सब्जियों और फलों के लिए।

से **ल्फ ड्रेइनिंग सिस्टम**
बटन दबाने मात्र से स्वच्छ और शीघ्र डिफ्रॉस्टिंग के लिए।

अ **धिक वस्तुओं का समावेश करता है**
सब रेफ्रिजरेटरों की तुलना में ऑल्विन में क्रिस्पेटर। शीतक ट्रे का सर्वाधिक परिमाण है।

इ **कहरा, ऊँचा और परिष्कृत**
अन्यों की तुलना में फर्श पर कम जगह लेता है।

वि **शाल श्रेणी**
ऑल्विन १६५ और ३०० लिटर के दो दरवाजोवाले और एक दरवाजेवाले मोडेल में, आंकर्षक रंगों के चयन के साथ आता है।

७ **वर्षों की विश्वस्त गॅरंटी**
वर्षों तक बिना तकलीफ सेवा के लिए।

दे **शभर में सेवा हेतु विशाल नेटवर्क**
एक फोन कॉल पर अविलंब सेवा के लिए।

ऑ **ल्विन का अनोखा संरक्षण करार प्राप्त करें ***

IS 1476 एक दरवाजेवाले सभी ऑल्विन रेफ्रिजरेटरों पर आइ एस आई चिह्न होता है।

ALLWYN

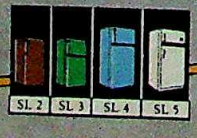

* अधिक विवरण के लिए अपने नजदीकी ऑल्विन क्षेत्र कार्यालय का संपर्क करें।

ऑल्विन सदा के लिए है।

हैदराबाद ऑल्विन के क्षेत्र कार्यालय : अहमदाबाद फोन: ४६३१८९, बनगलौर फोन: २३८८८५, भोपाल फोन: ६४१२२, भुवनेश्वर फोन: ५२२७१, बंबई फोन: ४९२७५७५, ४९२७५८६, ४९३४१७८, ४९२९०५५, कलकत्ता फोन: ४४०४३७, ४४६८५१, ४३३५७६, चंडीगढ फोन: ४१९४९, कडप्पा फोन:२२३०, एर्नाकुलम फोन:३६८००२, गौहती फोन: ३२६११, गाजियाबाद फोन: ८४३२०४, हैदराबाद फोन: ४३८७७, जबलपुर फोन: २२६६५, जयपुर फोन: ६५७२०, कानपुर फोन: ७४५३५, लखनऊ फोन: ३२४४४, मदुरै फोन: ३३२२, मंगलोर फोन: ४१२५, नई दिल्ली फोन: ७३४७४०, ७३०७१५, पटना फोन: ३८७४५, पूना फोन: ३९०२९, विजयवाडा फोन: ६२५४४, विशाखापट्टनम फोन: ६१६५२.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

MAA COMMUNICATIONS/HAL/A/HIN/88

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

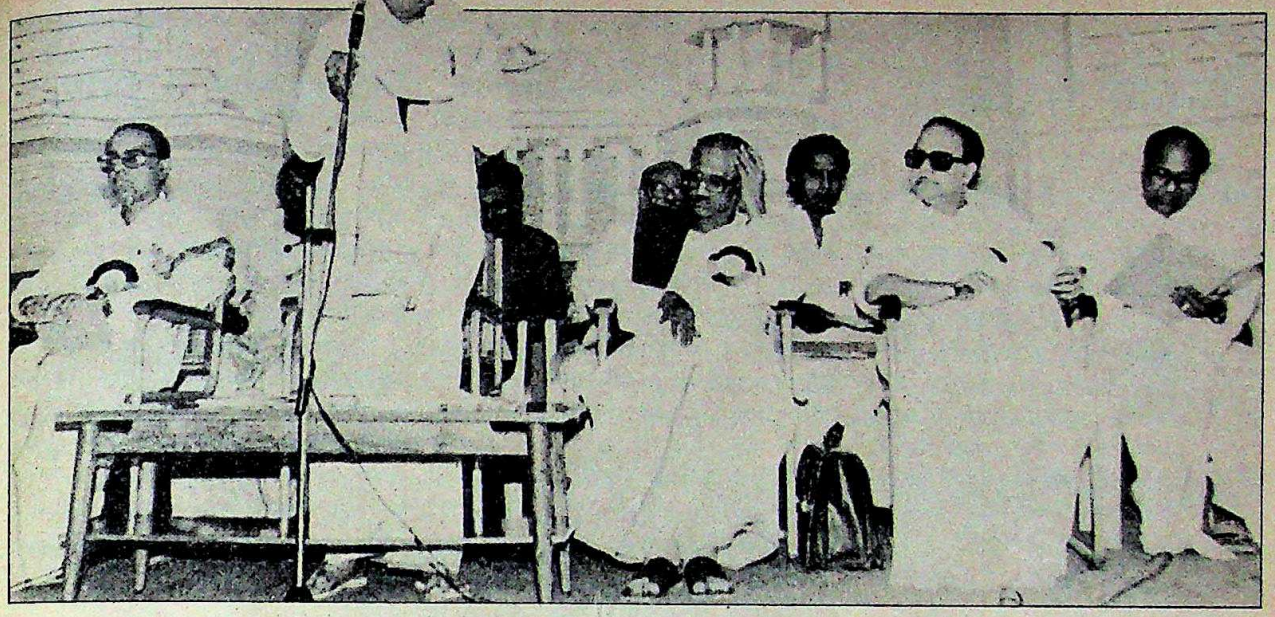

द्रमुक महापरिषद को संबोधित करते करुणानिधिः तीखे तेवर

तमिलनाडु

बचाव में हमला

अब द्रमुक भी मैदान में

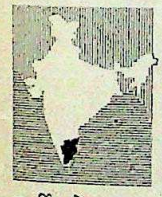

तमिलनाडु में राजीव गांधी के नेतृत्व में इंका नेताओं के हरकत में आते ही द्रमुक भी सक्रिय हो गई है. जनवरी में होने वाले चुनावों में अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में ला खड़ा करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ मुथुवेल करुणानिधि ने भी आखिर कमर कस ली है और चुनावी लड़ाई में कूद पड़े हैं. पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने वाले वी. गोपालस्वामी कहते हैं, "राजीव गांधी ने राज्य पर दानव की तरह हमला किया है लेकिन हमारे नेता करुणानिधि उन्हें एक छोटे पत्थर से ही मुंह की खिला देंगे." इस कथन से द्रमुक खेमे के आक्रामक तेवर ही जाहिर होते हैं.

राज्य में चुनावी बुखार के जोर पकड़ते ही द्रमुक ने लगभग एक साल के अंतराल के बाद पिछले पखवाड़े अपनी महापरिषद की बैठक बुलाई. दो-दिवसीय इस बैठक में 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसमें चुनावी कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया, उम्मीदवारों का चयन शुरू हुआ और कई कार्यक्रम तय किए गए. इंका पर सीधा हमला करने का फैसला किया गया.

करुणानिधि को उम्मीद है कि वे अपने स्थानीय असर से राजीव गांधी और राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर के मिले-जुले असर को खत्म कर देंगे. उन्होंने कहा, "राजीव अपनी यात्राओं में राज्य के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं. राज्य सरकार उनके हर दौरे पर गरीब जनता का 10 करोड़ रु. खर्च करती है."

इसमें कोई संदेह नहीं कि द्रमुक राष्ट्रपति शासन को बदनाम करने की जीतोड़ कोशिश करेगी. लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा. अलेक्जेंडर के शासन के दौरान प्रशासन निस्संदेह चुस्त-दुरुस्त हुआ है. फिर भी, करुणानिधि विश्वास से कहते हैं, "लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं. मौजूदा प्रशासन भी एमजीआर सरकार जितना ही भ्रष्ट है."

करुणानिधि को पृष्ठभूमि में धकेल देने वाले करिश्माई एमजीआर अब नहीं हैं, लिहाजा द्रमुक अध्यक्ष को उम्मीद है कि अब मतदाता उन्हें सिर-आंखों पर बिठा लेंगे. लेकिन द्रमुक की असल ताकत तो उसके कार्यकर्ताओं में निहित है. द्रमुक के 30,000 से अधिक ग्रामीण नेता 2 दिसंबर से राज्य भर में जनसभाएं करके "राजीव की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करेंगे."

जहां इंका अभी चुनावी गठजोड़ के लिए हाथ-पांव मार रही है, वहीं द्रमुक में उम्मीदवारों के चयन की कठिन लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लगता है पार्टी कुल मिलाकर विधानसभा की 234 में से 190 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हर उम्मीदवार से शुल्क के रूप में 500 रु. और अनुसूचित जाति के हर उम्मीदवार से 250 रु. मिलने से पार्टी का कोष भी एक करोड़ से बढ़कर चार करोड़ रु. हो जाएगा. करुणानिधि ने घोषणा की है कि वे खुद उम्मीदवारों का चयन करेंगे.

करुणानिधि के पुत्र स्टालिन भी निस्संदेह ही पिता की मदद करेंगे. पार्टी की पांच लाख सदस्यों वाली युवा शाखा के अध्यक्ष स्टालिन को करुणानिधि के उत्तराधिकारी के रूप में उभारा जा रहा है. पर द्रमुक मुख्यालय के सचिव अर्कोट वीरास्वामी कहते हैं, "स्टालिन को करुणानिधि ने नहीं थोपा है. वे कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं."

सांगठनिक क्षमता के मामले में इंका की स्थिति भी उतनी खराब नहीं है. मद्रास में 28 नवंबर को हुई इंका की विशाल सभा का मकसद लोगों के दिमाग से राष्ट्रीय मोर्चे की उद्घाटन रैली की याद मिटाना ही था.

जहां इंका और द्रमुक दोनों बड़ी चतुराई से अपने-अपने नेता को लोगों के बीच प्रतिस्थापित करने में लगी हैं, वहीं अन्ना द्रमुक के दोनों धड़े कुछ हद तक दरकिनार होते जा रहे हैं. जानकी गुट तो खास तौर पर गहरे संकट में है. उसमें जयललिता से अलग हुए गुट का अभी तक विलय नहीं हो पाया है. जानकी को फिल्म अभिनेता भाग्यराज का समर्थन खोने का भी खतरा बढ़ गया है जिससे वे बहुत चिंतित हैं. उधर, जयललिता गुट में उसके पूर्व कोषाध्यक्ष तिरुनावकारसु के लौट आने से उसकी स्थिति थोड़ी ठीक हो गई है.

बहरहाल, एमजीआर की कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई करुणानिधि और राजीव के बीच ही चल रही है.

—ललिता बिलीप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

विजयी बोम्मई

हेगड़े, देवगौड़ा की होड़ जारी

कर्नाटक के क्रिकेट प्रेमी मुख्यमंत्री सोमप्पा रायप्पा बोम्मई भी कुछ वैसे ही आशंकित थे जैसे 90 रन बनाने के बाद कोई बल्लेबाज हो उठता है. पिछले पखवाड़े वे असंतुष्ट नेता एच.डी. देवगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के बीच चली तनातनी में फंस गए. 20 नवंबर को उन्होंने अपने शासन के 100 दिन पूरे कर लिए. मगर यह पूरा दौर उनके लिए निश्चय ही एक कड़वे अनुभव का दौर था. पर बोम्मई ने तत्काल चैन की सांस ली. उन्हें सांसत में डालने वाले दोनों लोगों की अलग-अलग विदेश यात्राओं से दोनों गुटों में अस्थायी युद्धविराम हो गया था (हेगड़े एक पारिवारिक शादी के सिलसिले में और देवगौड़ा सिंचाई परियोजनाओं के अध्ययन के लिए विदेश गए थे).

विवाद का ताजा दौर प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर दोनों गुटों द्वारा अपने-अपने उम्मीदवारों को काबिज कराने की रस्साकशी के साथ उभरा. हेगड़े गुट द्वारा मुख्यमंत्री पद की लड़ाई जीतने के बाद से ही देवगौड़ा गुट पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष पद पाने के लिए बेताब था. पर हेगड़े गुट इस पद पर भी काबिज रहा (मौजूदा अध्यक्ष एम.पी. प्रकाश हेगड़े समर्थक हैं). यही नहीं, हेगड़े अपने एक अन्य समर्थक डॉ. जीवराज अल्वा को पार्टी का महासचिव बनवाने में भी कामयाब रहे.

देवगौड़ा गुट का दावा है कि बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाए जाते वक्त उसके उम्मीदवार सिद्धारमैया को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाने का वादा किया गया था. पर हेगड़े समर्थक इसका जोरदार खंडन करते हैं. उनके मुताबिक यह आश्वासन इस शर्त पर दिया गया था कि बोम्मई सर्वसम्मति से चुने जाएंगे. देवगौड़ा चूंकि बोम्मई के खिलाफ खड़े हुए थे, इसलिए इस आश्वासन का कोई मतलब ही नहीं रहा.

हेगड़े ने यह बयान देकर मामले को और पेचीदा बना दिया कि देवगौड़ा बिना शर्त बोम्मई मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और उन्होंने आग्रह करके अपना पसंदीदा सिंचाई विभाग पाया था. गुस्से में देवगौड़ा ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, "अब हेगड़े की क्या बिसात है? विभाग बांटना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है. मुख्यमंत्री बोम्मई अगर कह दें कि मैंने फलां विभाग मांगा था तो मैं उसका जवाब दूंगा."

देवगौड़ा गुट इस मामले को नई दिल्ली तक ले गया, जहां जनता दल में विलय के फैसले की पुष्टि के लिए जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी. उन्होंने धमकी दी कि जब तक सिद्धारमैया को प्रकाश की जगह प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, वे विलय का विरोध करेंगे और जनता पार्टी की पुरानी पहचान बरकरार रखेंगे. लेकिन न तो हेगड़े गुट ने और न असंतुष्टों को शह देने वाले अजीत सिंह और चंद्रशेखर ने ही इन धमकियों पर कोई ध्यान दिया. हालांकि बैठक में इस गुट के नेताओं ने विरोध जताते हुए जोरदार भाषणबाजी की और हेगड़े समर्थकों से उनके समर्थक उलझ भी पड़े.

श्याम टेकवानी

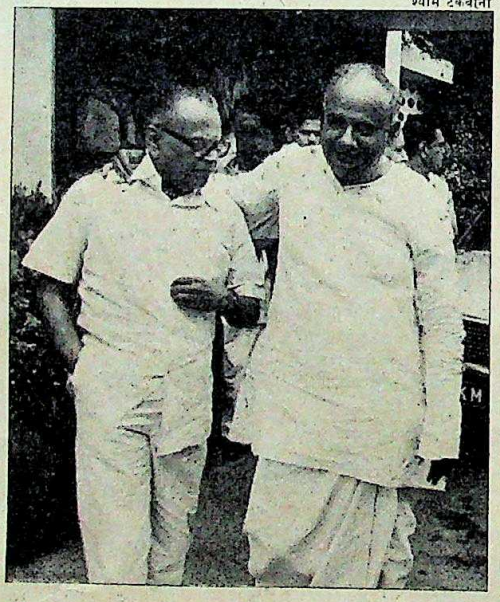

मुख्यमंत्री बोम्मई के साथ देवगौड़ा: आपसी कलह

इसके बावजूद असंतुष्ट गुट का दावा है कि राष्ट्रीय परिषद द्वारा विलय की औपचारिकताएं पूरी करने का अधिकार अजीत सिंह को दिए जाने से जीत उसी की हुई है. उसका तर्क है कि इन औपचारिकताओं में नई पार्टी की राज्य इकाइयों का पुनर्गठन भी शामिल है. असंतुष्ट इस बात पर भी खुश हैं कि राष्ट्रीय परिषद में जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर द्वारा पेश किए गए विलय की पुष्टि के प्रस्ताव का अनुमोदन हेगड़े ने नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बोम्मई ने किया. व्यंग्य बाण छोड़ते हुए देवगौड़ा कहते हैं, "क्या ये वही हेगड़े हैं, जिन्होंने कहा था कि वे अजीत सिंह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय परिषद को नहीं मानते? आश्चर्य है, अब वे उसी परिषद की बैठक में कैसे हाजिर हुए?" पर हेगड़े समर्थक इसी पर अपनी जीत का डंका पीटते हुए खुशी जाहिर करते दिख रहे थे कि असंतुष्ट फिलहाल प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बदलने में सफल नहीं हो पाए.

दो गुटों के इस सत्ता संघर्ष में जीत का सेहरा आखिर चतुर बोम्मई के सिर ही बंधा है. विलय प्रस्ताव का अनुमोदन कर बोम्मई अपने पूर्ववर्ती हेगड़े की छाया से निकलकर अपनी स्वतंत्र छवि विकसित करने में कामयाब हुए. इसके बाद उन्होंने अपना दांव चला कि नई पार्टी की राज्य इकाइयों का पुनर्गठन अजीत सिंह नहीं बल्कि जनता दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह करेंगे.

दो गुटों के इस सत्ता संघर्ष में जीत का आखिरी सेहरा चतुर बोम्मई के माथे ही बंधा. विलय प्रस्ताव का अनुमोदन कर उन्होंने अपने को हेगड़े की छाया से मुक्त कर लिया

दरअसल, हेगड़े और देवगौड़ा के आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच चुप्पी साधकर बोम्मई ने अपने विवेक का ही परिचय दिया. इससे दोनों गुटों के बीच उनकी साख बढ़ी ही. इस उठापटक के बीच भी वे समय निकालकर आत्मविश्वास से भरे नवजोत सिंह सिद्धू को रिचर्ड हेडली की गेंदों का सामना करते देखने जाते रहे. वे कबूल करते हैं कि तनाव से भरे पिछले पखवाड़े में उनका धूम्रपान बहुत बढ़ गया था. फिर वे आत्मविश्वास से कहते हैं, "अब मैं बिलकुल चैन से हूं." लेकिन उनका यह चैन अस्थायी साबित हो सकता है. कर्नाटक का यह झगड़ा विपक्षी एकता में रोड़ा बने रहने का अंदेशा है.

—चिदानंद राजघट्टा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हरियाणा

घृणित साजिश

कैथल में जघन्य हत्याएं

पंजाब के खून के प्यासे आतंकवादी नजदीकी राज्य हरियाणा को अपने घृणित खेल का मैदान बनाते जा रहे हैं. पिछले पखवाड़े अंधाधुंध हत्याएं कर उन्होंने अपने रुख का इजहार कर दिया. कुरुक्षेत्र जिले के कैथल शहर की मुख्य सड़क पर जीप में गुजरते हुए उन्होंने जो भी रास्ते में नजर आया उसे गोलियों का निशाना बना डाला.

पांच वर्षीय ममता और आठ तथा तीन साल के उसके भाई-बहनों के लिए आतंकवाद का मतलब है: सरकारी अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष और पिता की मौत. ये लोग बाजार से लौट रहे थे कि व्यस्त चंदाना गेट के पास एकाएक बिजली गुल हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया.

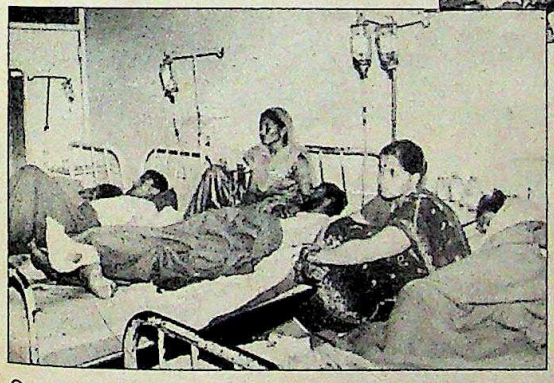

फिर यमदूतों की गोलियां आईं और वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे. ये बच्चे बच भी गए तब भी उनका भविष्य तो अंधकारमय हो गया है. मां को पहले ही खो चुके ये बच्चे अब एकदम अनाथ हो गए हैं.

लेकिन उस शाम केवल यही बच्चे हत्यारों की गोलियों का निशाना नहीं बने. आतंकवादियों ने उस मनहूस शाम को जिन 23 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा उनमें 10 वर्ष से कम आयु के आठ बच्चे भी थे. जालिम हत्यारों की गोलियों ने शिकार चुनने में कोई भेद नहीं किया. उनकी गोलियों ने हिंदू, मुसलमान, सिखों और औरतों तक पर घाव बना दिए.

शहर में उन्होंने तीन जगहों पर हमले किए. जीप पर सवार छह या सात हत्यारों ने अपने मुंह ढांप रखे थे. उन्होंने सबसे पहले रेलवे गेट इलाके के नजदीक हमला करके तीन लोगों को मार डाला और करीब 12 लोगों को घायल कर दिया. इसके बाद आधा किलोमीटर दूर चंदाना गेट इलाके में आठ लोगों को यमलोक पहुंचाया और प्रताप गेट इलाके की तरफ कूच करते हुए रास्ते के दोनों ओर एके-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए और बारह लोगों को अपना शिकार बना डाला.

कैथल में सामूहिक दाह संस्कार; और स्थानीय अस्पताल में कुछ घायल

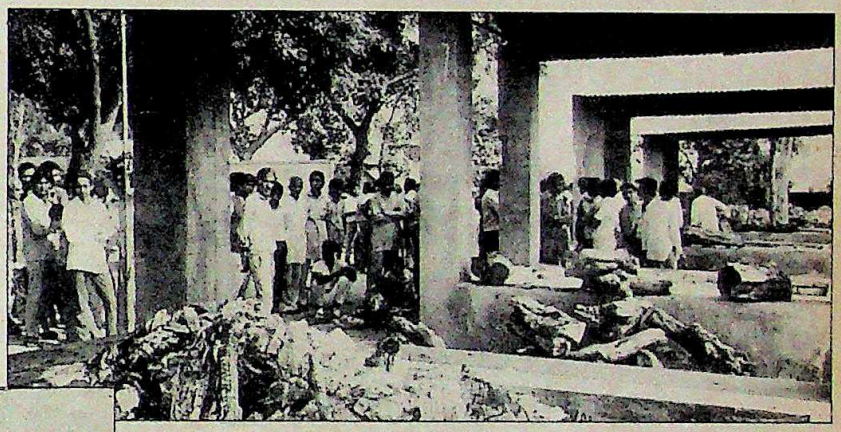

हादसे का दुखद पहलू यह था कि हत्यारों ने अपने समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने की नीयत से यह कांड किया

कैथल नरसंहार का एक गंभीर पहलू है. आतंकवादियों ने पंजाब-हरियाणा सीमा के इस नाजुक इलाके में हत्याएं सांप्रदायिक तनाव भड़काने के उद्देश्य से कीं. अगले ही दिन 'गुरु परब' (गुरु नानक जन्मदिवस) होने की वजह से नजदीकी गांवों के सैकड़ों सिख शहर के मंजी साहिब और नीम साहिब गुरद्वारों में जमा होने वाले थे. 'गुरु परब, उत्सव के 10 घंटे पहले हत्यारों के हमलों से साफ जाहिर हो जाता है कि उनके इरादे क्या थे. उस वक्त सैकड़ों सिख अगले दिन के उत्सव के लिए कैथल के गुरद्वारों में इकट्ठे हो चुके थे. निश्चित ही आतंकवादी चाहते थे कि उनकी कार्रवाई से उनके अपने (सिख) समुदाय के खिलाफ हिंसा शुरू हो जाए और फिर खून-खराबे का ऐसा क्रम चले जिसमें वे अपनी रोटी सेंक सकें.

और हत्यारों के मंसूबों के माफिक ही स्थानीय इंका नेताओं ने मुख्यमंत्री देवीलाल से इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला जलाया. साथ ही सिविल अस्पताल और मरघट पर भी सैकड़ों लोग जमा हो गए. उत्तेजक जुलूस निकाला गया जिसमें शामिल लोगों ने गुरद्वारे में तोड़फोड़ की तथा कुछ लोगों से हाथापाई भी. उपमुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता का दावा है कि जुलूस की अगुआई इंकाई कर रहे थे.

देवीलाल को नीचा दिखाने के हर मौके का पूरा-पूरा फायदा उठाने की जुगत में भिड़ी केंद्र सरकार भी तुरंत हरकत में आई. केंद्रीय गृहमंत्री बूटासिंह ने हत्याकांड पर चिंता जताते मुख्यमंत्री को फोन किया. यही नहीं, तुरंत ही अर्धसैनिक बलों की चार बटालियनें भी हरियाणा रवाना कर दी गईं. हालांकि देवीलाल सरकार अरसे से इस सहायता की मांग कर रही थी.

लेकिन तारीफ की बात रही लोगों का व्यवहार. उन्होंने संयम नहीं खोया. एक लाख की आबादी वाला पूरा शहर इस मुसीबत से निपटने के लिए एकजुट हो गया. प्राइवेट डॉक्टर मदद के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच गए और दवाई के दुकानवालों ने उदारता का परिचय देते हुए दवाइयों के पैसे लेने से इनकार कर दिया.

हालांकि इस साल कुरुक्षेत्र जिले में आतंकवादियों का यह चौथा हमला था लेकिन स्पष्ट है कि पुलिस के पास ऐसे खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त साजो-समान अभी भी नहीं है.

पंजाब के आतंकवादियों के शिकारगाह बनते इस राज्य में हालांकि आज लोगों की समझदारी और संयम बरकरार है. लेकिन तनाव और बदले की भावना किसी भी वक्त धैर्य का बांध तोड़ सकती है.

—विपुल मुद्गल, कैथल में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हरियाणा

मौत पर आसमान टूटा

देवीलाल की पौत्रवधू की मृत्यु पर इंकाई बवाल

तारीख: 11 नवंबर. समय: शाम 7.15. स्थान: चौटाला गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल का फार्म हाउस. देवीलाल के बड़े बेटे राज्यसभा सदस्य ओमप्रकाश चौटाला के अनुसार फार्म हाउस में उस समय उनकी छोटी पुत्रवधू सुप्रिया, उनके बड़े बेटे अजय सिंह, पांच मेहमान और दुर्गा नाम का नौकर था. मुख्यमंत्री की पत्नी हरकी देवी आधे घंटे पहले गांव में परिवार के पुश्तैनी मकान में चली गई थीं. देवीलाल खुद पास के ही एक रेस्तरां में राजस्थान के दो विधायकों से मिलने गए थे. चौटाला के अनुसार उनके छोटे बेटे 22 वर्षीय अभय सिंह अपने दादा से मिलने तुरंत ही रवाना हुए थे.

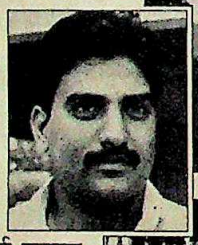

चौटाला के एक बयान के अनुसार एक कमरे में सुप्रिया के अलावा सभी लोग बैठे थे. तभी उन लोगों को लगा कि पिछवाड़े जैसे कोई पटाखा छोड़ा गया. अचानक दुर्गा भागता हुआ आया और उसने बताया कि सुप्रिया अपने कमरे में खून से लथपथ मरी पड़ी है. देवीलाल परिवार का दावा है कि सुप्रिया जब अपने पति के सूटकेस से कपड़े निकाल रही थी तो .32 बोर की लाइसेंसशुदा पिस्तौल अचानक छूट गई और सुप्रिया को गोली लग गई.

लेकिन इंका ने मुद्दे पर संसद को जैसे सिर पर उठा लिया. सुप्रिया की मौत को 'हत्या' बताते हुए घटना की जांच की मांग की गई. 48 घंटे के अंदर-अंदर यह दुर्घटना विवाद का मसला बन गई.

एक आरोप यह भी था कि सुप्रिया के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और मुख्यमंत्री के परिवार ने उसका दाह संस्कार करने में जल्दबाजी की. इंका नेता और पूर्व शिक्षामंत्री जगदीश नेहरा ने कहा, "यह साफ तौर पर सबूतों में हेरफेर करने का मामला है." लेकिन राज्य के गृहमंत्री संपत सिंह ने इसके जवाब में कहा कि दाह संस्कार सुप्रिया के पिता और बाकी रिश्तेदारों के सामने किया गया. उन्होंने शव के पोस्ट-मार्टम के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जिन्हें नेहरा ने जाली बताकर नकार दिया. 18 और 19 नवंबर को नेहरा ने डबवाली और चंडीगढ़ में रैलियां करवाईं और मामले की सीबीआई द्वारा जांच न कराने के लिए देवीलाल से इस्तीफे की मांग की. इस बीच निर्दलीय सांसद हरद्वारीलाल भी बीच में कूद पड़े और घोषणा कर दी कि वे लोकहित मुकदमा ठोककर सुप्रिया को न्याय दिलवाएंगे.

लेकिन घटना का राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश चंडीगढ़ में इंका द्वारा आयोजित रैली से जाहिर होती है. रैली के लिए पुनर्वास कॉलोनियों से जुटाए गए लगभग 300 कार्यकताओं को रैली का मकसद भी नहीं पता था. 26 सेक्टर की मजदूर कॉलोनी की शांति देवी ने बताया, "कालोनी के नेता शाम लाल ने मुझसे कहा कि यहां मुझे प्लॉट की पर्ची मिलेगी."

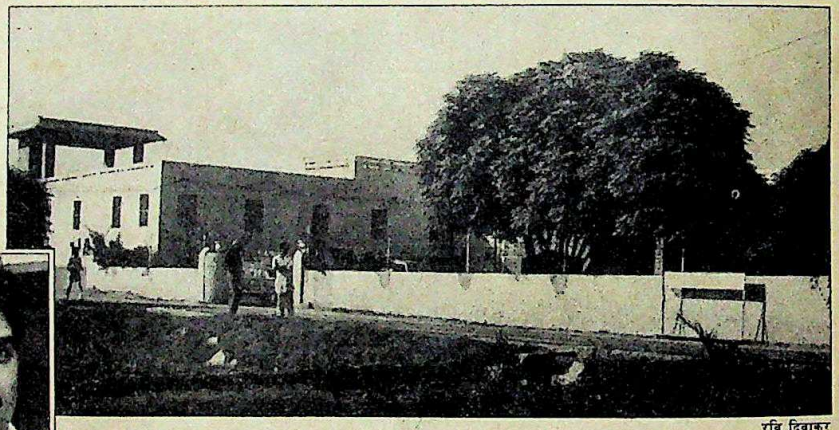

रवि दिवाकर

देवीलाल का फार्महाउस; अभय (इनसेट में); कांता के साथ सुप्रिया (नीचे दाएं)

मगर सुप्रिया के पिता मटोरिया को कोई साजिश नजर नहीं आती. और तो और उन्होंने दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी नाबालिग बेटी कांता से अभय की शादी का प्रस्ताव रखा है. यहां गौरतलब बात यह भी है कि मटोरिया लोकदल नहीं बल्कि कट्टर कांग्रेस समर्थक हैं.

लेकिन मुख्यमंत्री के विरोधी इसी मुद्दे— अभय और कांता के कथित प्रेम संबंध—को कथित हत्या का कारण बताते हैं. दूसरी मान्यता यह है कि सुप्रिया ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उसके पति के कई औरतों से संबंध थे. लेकिन मटोरिया कहते हैं, "मेरी बेटी का अपने पति के साथ कोई झगड़ा नहीं था."

अभय ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत में यह स्वीकार किया कि वे हिसार में कांता से होस्टल में अक्सर मिलने जाया करते थे लेकिन साथ में हमेशा सुप्रिया भी होती थी. उन्होंने कहा, "साफ है कि कुछ लोग हमारे दादा से राजनैतिक बदला लेना चाहते हैं. अगर मुझे अपनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पत्नी की हत्या ही करनी होती तो कई सुरक्षित तरीके हैं."

इस मामले में विसंगतियां भी सामने आ रही हैं. मसलन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उसने शव का पोस्ट-मार्टम चौटाला गांव के एक अस्पताल में किया, जबकि बाकी लोगों के (जिनमें ओमप्रकाश चौटाला और मटोरिया भी शामिल हैं) अनुसार पोस्टमार्टम फार्म-हाउस पर ही किया गया जहां सुप्रिया की मौत हुई थी. पुलिस प्रवक्ता एम.एस. मलिक के अनुसार सुप्रिया के माता-पिता के वहां पहुंचने तक शव को छेड़ा ही नहीं गया था. लेकिन मटोरिया का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार शव को देखा तो वह बिस्तर पर रजाई में पड़ा था.

इसके अलावा मटोरिया के अनुसार उन्होंने सुप्रिया के बाएं कान के नीचे गोली का निशान देखा था, जबकि पोस्टमार्टम और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गोली गले में सामने की ओर से अंदर जाकर गले के पीछे से निकली थी.

यदि परिवारवालों के विरोधाभासी बयानों को हादसे के गम के कारण चीजों को ठीक से याद न रख पाना मान लिया जाए तो भी कई और सवाल इस रहस्य को गहरा देते हैं. क्या ओमप्रकाश चौटाला के इस बयान को सही माना जा सकता है कि दो पाउंड वजन वाली पिस्तौल का घोड़ा सुप्रिया के किसी कपड़े के दबाव से दब गया? फिर, अपनी खुद की लाइसेंसशुदा रिवॉल्वर होते हुए भी अभय सिंह अपने भाई अजय सिंह की पिस्तौल क्यों रखे हुए थे? घटनास्थल से महज दस फुट की दूरी पर एक कमरे में बैठे अजय सिंह और बाकी रिश्तेदारों ने पिस्तौल की आवाज को पटाखे की आवाज कैसे समझ लिया?

इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिलें, लेकिन इस प्रकरण से इतना जरूर उजागर हो गया कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए किसी भी मर्यादा का उल्लंघन भारतीय राजनीति का चरित्र बन गया है. सैकड़ों मौतें होती रहें तो भी कोई उफ नहीं कर सकता और एक मौत पर आसमान सिर पर उठा लिया जा सकता है.

—विपुल मुद्गल

बात पते की: कलमची

अपने अपने आयोजन

अंग्रेजी भाषा में 'डेढ़ सौ वर्ष' शब्द को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए हमें 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का हृदय से आभारी होना चाहिए, खास तौर पर इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोई 150 साल पहले ही इसे 'विलुप्त' घोषित कर दिया गया था (अब समझ में आ रहा है कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को 'बोरी-बंदर की बुढ़िया' क्यों कहा जाता है). लेकिन फिलहाल तो उस भानुमती के पिटारे में झांकने की जरूरत है जिसे टाइम्स ने शायद अनजाने में ही खोल दिया है.

शायद अपने उत्साह की रौ में वह अब 'टाइम्स स्कूप' नामक एक विशेष आइसक्रीम बेचने की योजना बना रहा है. उसकी योजना एक साल के लिए एक रेस्तरां भी लेने की है जिसका नाम बदलकर 'टाइम्स स्क्वायर' रखा जाएगा. लेकिन अगर दूसरे राष्ट्रीय अखबार भी टाइम्स के ही नक्शेकदम पर चलने का फैसला कर लें तब नजारा कुछ इस तरह होगा:—

'द हिंदू' अपने परिणामी वर्ष समारोहों की शुरुआत मद्रास के मरीना समुद्र तट पर एक रॉक संगीत कार्यक्रम के साथ करने का फैसला करता है. इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं—स्वीडन का लोकप्रिय रॉक ग्रुप 'भुगतान उजागर मंडली' और उसकी मुख्य गायिका चित्रा सुब्रमण्यम. इसके बाद वे 'हिंदूवाद' शीर्षक से एक भारी-भरकम स्मारक अंक निकालते हैं जिसमें पत्रकारिता की भाषा को 'द हिंदू' के अनूठे योगदान का वर्णन होता है. फिर शानदार समापन समारोह होता है जिसमें 'हिंदू हमला' शीर्षक से एक प्रदर्शनी लगाई जाती है. इसमें बोफोर्स संबंधी दस्तावेजों के सभी 200 पृष्ठ रखे जाते हैं.

'हिंदुस्तान टाइम्स' भी भला क्यों पीछे रहता? सो वह अपना 'अपरिणामी वर्ष' मनाता है. इस मौके पर वह 'राजीव वार्ता' शीर्षक से 200 पन्ने का विशाल अंक निकालता है. यह इंटरव्यू संपादक हरिकृष्ण दुआ ने लिया है. लेकिन सबसे दिलचस्प समारोह होता है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहां उन सभी 75,000 जोड़ों को आमंत्रित किया गया है जो अखबार के वैवाहिक विज्ञापनों के मार्फत परिणय सूत्र में बंधे.

उधर 'द स्टेट्समैन' 'अस्तित्व रक्षा वर्ष' अपनी छवि के अनुरूप मनाता है. समारोह में शुरुआत एक सम्मेलन से होती है जिसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाता है. इसके बाद एक साल तक चलने वाला विज्ञापन अभियान शुरू हुआ. हुगली नदी पर ललित सूरी और सतीश शर्मा जैसे खास आमंत्रितों और प्रमुख सरकारी नेताओं के नौका विहार के साथ समारोह खत्म हुआ.

'इंडियन एक्सप्रेस' 'गद्दी छुड़ाओ वर्ष' मनाता है. इस अवसर पर वह 300 पृष्ठों का एक विशालकाय अंक निकालता है जो अरुण शौरी का ही एक लेख है. शीर्षक है "खंडन, खंडन और बस खंडन! और क्या है प्रधानमंत्री जी?" इसके बाद 'सार्वजनिक जीवन में नैतिकता' पर एक सेमिनार होता है, इसमें राम जेठमलानी, ए.जी. नूरानी, सोली सोराबजी, चंद्रास्वामी, नुस्ली वाडिया और एस. गुरुमूर्ति जैसे प्रमुख पत्रकार भाग लेते हैं. समापन समारोह गोयनका के बंबई के पेंटहाउस में होता है जहां इंडियन एक्सप्रेस विपक्षी मोर्चे में शामिल हो जाता है. उसका नाम जनता एक्सप्रेस हो जाता है.

कार्टून: मंजुला पद्मनाभन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भोपाल गैस हादसा

नाउम्मीदी का आलम

भोपाल गैस हादसे के चार साल बाद भी इसके पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत या मुआवजा नाममात्र ही मिला है. तब यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी मिथाइल आइसोसायनेट (मिक) गैस ने करीब 3,000 लोगों की जान ले ली थी और हजारों लोगों को धीमी मौत की राह पर धकेल दिया था. कंपनी की लापरवाही और सरकारी घपलों ने इतिहास के इस सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के तीखेपन को और बढ़ाया ही है. एक रिपोर्ट:

चार साल बाद एक बार फिर वही सब दोहराया जाएगा. टीवी के परदे पर गैसपीड़ितों के पीले पड़े चेहरे फिर दिखेंगे, रैलियां और प्रार्थना-सभाएं की जाएंगी, 'बहुराष्ट्रीय दानव' के पुतले जलाए जाएंगे, लंबे-चौड़े भाषण होंगे, कसमें खाई जाएंगी, वादे किए जाएंगे. इसी पखवाड़े भोपाल हादसे की चौथी बरसी जो होगी! मगर इस तमाम हो-हंगामे के बाद फिर दुनिया का कारोबार उसी तरह चलने लगेगा जैसे चलता रहा था.

लेकिन 26 वर्षीय कैलाश पंवार की वह दुनिया कभी नहीं लौटेगी जो 3 दिसंबर 1984 के पहले की थी. उस भयावह हादसे के बाद उन्हें मरा हुआ मानकर मुर्दाघर जाने वाले एक ट्रक पर शवों के ढेर में फेंक दिया गया था. सड़ती लाशों के ढेर में से किसी तरह बाहर आने में तो वे कामयाब रहे पर उनका जीवन पंगु-सा होकर रह गया. दिल्ली के एक अस्पताल में पड़े वे अपनी तबाही का कुछ इस तरह बयान करते हैं, "मेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है." वे ड्राइवर हुआ करते थे पर अब वे गाड़ी नहीं चला पाएंगे. उनकी पत्नी पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई करके जो भी आमदनी कर पाती है उसी पर परिवार को निर्भर रहना होगा.

हादसे से पीड़ित हजारों लोगों में पंवार एक उदाहरण ही हैं. इन सभी लोगों के लिए मौत का खौफ अभी भी बरकरार है. आज भी औसतन हर रोज एक-न-एक गैसपीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है. इस तरह दिसंबर 1984 में हुई 1800 मौतों को मिलाकर चार साल में 3289 लोगों की मौत हो चुकी है. मिक गैस ने जैविक और पर्यावरणीय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कमलेश जैमिनी

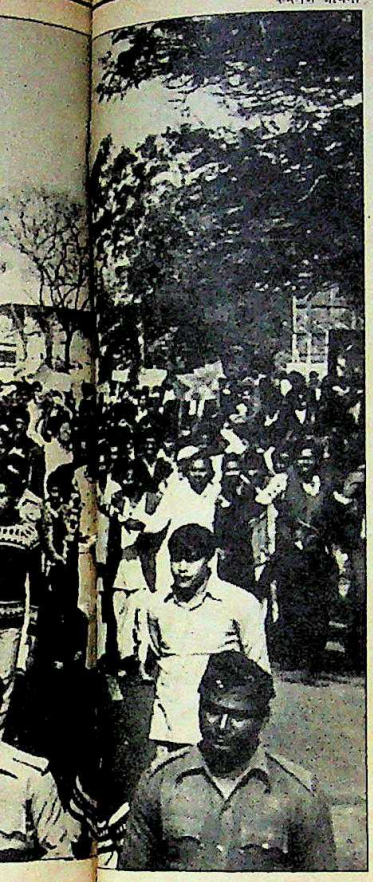

प्रकाश हतवालने

हर रोज औसतन एक गैसपीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है. इस तरह दिसंबर 1984 में हुई 1800 मौतों को जोड़कर चार साल में 3289 लोगों की मौत हो चुकी है. मिक गैस ने जैविक और पर्यावरणीय संतुलन को तहस-नहस करके विभिन्न रोगों के लिए द्वार खोल दिए हैं

संतुलन को तहस-नहस करके लोगों की प्रतिरोध क्षमता को बेहद कमजोर कर विभिन्न रोगों के लिए द्वार खोल दिए हैं.

हादसे के बाद बच गए लोग अब यही कहते हैं कि न बचते तो ही अच्छा रहता क्योंकि राहत या मुआवजा मिलने की आशा के क्षीण होते जाने से वे दिनोदिन निराश होते जा रहे हैं. चार साल बाद भोपाल सिर्फ औद्योगीकरण के भारी जोखिम का ही नहीं बल्कि उद्योगपति वर्ग के उपेक्षा भाव और सरकारी घपले का भी प्रतीक बन गया है.

गैसपीड़ितों को अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से बस 1500 रु. की रकम ही मिल पाई है. यहां तक कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले सरकारी ज्ञापन में भी कहा गया है कि "राहत/पुनर्वास के लिए अभी तक उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं. इसके लिए नए और बड़े कदम उठाने की जरूरत है."

मगर यह भी हालत का मामूली जायजा ही है. सचाई यह है कि गैसपीड़ित एक ऐसी जटिल कानूनी लड़ाई के मोहरे बन गए हैं, जिसे वे न तो समझ सकते हैं और न लड़ सकते हैं. भारत सरकार के तथाकथित अफसरशाहों और बहुराष्ट्रीय कंपनी के ताकतवर आकाओं ने राहत देने से कहीं ज्यादा रकम अदालती लड़ाई में ही खर्च कर दी है.

1985 में बने एक कानून के अनुसार राहत, इलाज और अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी) से हर्जाना प्राप्त करने की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है. यूनियन कार्बाइड को ही हादसे के लिए जिम्मेदार माना जाता है. भोपाल कारखाने को यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड (यूसीआईएल) चलाती है. इस सहयोगी कंपनी के ज्यादातर शेयर यूसीसी के पास ही हैं. सरकार द्वारा जुटाए गए सबूतों के अनुसार, कारखाने का काम-काज भारतीय ही चलाते हैं पर भारतीय कारोबार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिका से ही किए जाते रहे हैं.

आर.सी. साहू

देव ने यूसीसी को 350 करोड़ रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया. उम्मीद के मुताबिक यूसीसी ने इसके खिलाफ अपील दायर की

गैसपीड़ितों को मुआवजा दिलाना ही फिलहाल मुख्य मुद्दा है. कार्बाइड के जन संपर्क विभाग के उपाध्यक्ष और इसके प्रमुख प्रवक्ता रोनाल्ड विशार्ट ने पिछले पखवाड़े 'इंडिया टुडे' को बताया कि मुकदमा तो अब लगभग आखिरी दौर में पहुंच गया है. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश आर.एस. पाठक के हाल के उस आग्रह को सही बताया कि दोनों पक्षों को "एकदम नए सिरे से बातचीत शुरू करनी चाहिए."

लेकिन गैसपीड़ितों ने मुआ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"सरकार के कामकाज से हमारी निराशा को भोपाल के बाहर का कोई नहीं समझ सकता"

अनिल सदगोपाल
सुप्रीम कोर्ट समिति के गैरसरकारी सदस्य

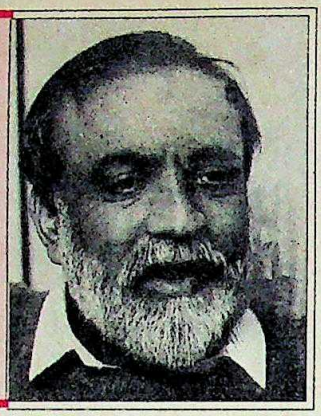

"सरकार को समझौते से पहले सक्रिय संगठनों से सलाह लेनी चाहिए... नहीं तो हम विरोध करेंगे"

आलोक प्रताप सिंह
जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चा

वजे की उम्मीद लगभग छोड़ दी है. साल भर पहले सरकार और यूसीसी के बीच करीब 60 करोड़ डॉलर पर लगभग समझौता हो गया था (देखें इंडिया टुडे, 15 दिसंबर, 1987). लेकिन उस समय भारी विरोध के मद्देनजर सरकार पीछे हट गई थी.

गैसपीड़ितों के बीच सक्रिय कुछ गुटों ने समझौते का विरोध किया है क्योंकि उन्हें लगा कि समझौते में यूसीसी और यूसीआईएल के आकाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को भी रफा-दफा करना शामिल होगा. भोपाल गैसपीड़ित उद्योग संगठन के जब्बार खां ने कहा, "भोपाल जैसे हादसे आगे न हों इसके लिए जवाबदेही तय करनी ही होगी." जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चा के आलोक प्रताप सिंह ने कहा, "सरकार को कार्बाइड के साथ किसी समझौते पर बातचीत करने से पहले यहां के सक्रिय संगठनों से जरूर सलाह करनी चाहिए."

अब स्थिति यह है कि अदालती लड़ाई जारी है. सैकड़ों सुनवाइयों, अमेरिकी और भारतीय अदालतों में 5.5 करोड़ डॉलर की फीस चुकाने और मुकदमे के चार साल घिसटने के बाद भी मंजिल दूर-दूर तक नहीं दिख रही है. पहले तो न्यूयॉर्क में मुकदमा दर्ज करने में ही चार महीने की देरी हुई. साल भर बाद मुकदमा भारत में वापस भेज दिया गया, पर भोपाल जिला अदालत में मुकदमा दर्ज करने में सरकार ने और चार महीने लगा दिए. जिला जज ने महीनों तक सुनवाई नहीं शुरू की ताकि सरकार को यूसीसी के साथ समझौते के लिए मोहलत मिले.

जब समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आई तब भोपाल के जिला जज एम. डब्ल्यू. देव ने यूसीसी को आदेश दिया कि वह 350 करोड़ रुपए के अंतरिम मुआवजे का भुगतान करे. लग रहा था मुकदमा अनंत काल तक खिंच जाएगा क्योंकि यूसीसी 5.8 लाख दावेदारों में से हरेक को अदालत में हाजिर होने और उनसे जिरह करने की मांग जरूर करेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "सभी दावा पत्रों को अदालत में ले जाने के लिए करीब 40 ट्रकों की जरूरत होगी. और गवाहों से जिरह में तो 300 साल लग जाएंगे." जैसी कि उम्मीद थी, यूसीसी ने देव के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी.

इस साल 4 अप्रैल को हाईकोर्ट ने फैसला किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत देव का अधिकार इस मामले में जायज नहीं ठहरता. लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.के. सेठ ने अपने फैसले में कहा कि मामले के अंतिम फैसले से पहले अंतरिम मुआवजा अदा करने का आदेश देने के लिए देव के पास यूसीसी की जवाबदेही के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत थे. यूसीसी ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जो खारिज हो गई.

मामला यहीं नहीं खत्म हुआ. 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार और यूसीसी की याचिकाएं मंजूर कर लीं. सरकार ने अंतरिम मुआवजे को 350 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ रु. करने को चुनौती दी. कार्बाइड ने दोनों अदालतों द्वारा ऐसे मामले में अंतरिम मुआवजा अदा करने का आदेश देने के

कार्बाइड मामला
लंबी खिंचती लड़ाई

1985

20 फरवरी: भारत सरकार ने गैसपीड़ितों के प्रतिनिधित्व का एकमात्र अधिकार लेने के लिए अध्यादेश जारी किया. (बाद में इसे कानून का रूप दिया गया).

8 अप्रैल: भारत सरकार ने अमेरिका में यूसीसी पर 3 अरब डॉलर हर्जाने का दावा ठोका.

19 अप्रैल: अदालत के कहने पर यूसीसी ने 50 लाख डॉलर अंतरिम राहत देने की पेशकश की.

1986

23 मार्च: यूसीसी और गैसपीड़ितों के अमेरिकी वकीलों के बीच 35 करोड़ डॉलर पर हुए समझौते को भारत ने रद्द कर दिया.

12 मई: अमेरिकी अदालत ने यूसीसी को भारतीय अदालतों के सामने उपस्थित होने का आदेश देकर मामले को भारत भेज दिया.

5 सितंबर: भारत सरकार ने भोपाल जिला अदालत में यूसीसी पर 3,900 करोड़ रु. हर्जाने का मामला दायर किया.

1987

2 अप्रैल: न्यायाधीश एम. डब्ल्यू. देव ने 'समाधेय अंतरिम राहत' की सलाह दी.

17 अगस्त: सरकार ने यूसीसी की 2.1 करोड़ रु. की पेशकश नामंजूर कर दी.

नवंबर: सरकार ने 60 करोड़ डॉलर मांगते हुए समझौते को विफल कर दिया.

17 दिसंबर: देव ने यूसीसी को 350 करोड़ रु. अंतरिम राहत देने को कहा.

1988

18 जनवरी: यूसीसी ने देव के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की.

4 अप्रैल: हाईकोर्ट ने यूसीसी की जिम्मेदारी मानी और 250 करोड़ रु. अंतरिम हर्जाना देने का आदेश दिया.

28 जुलाई: एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया कि न भारत सरकार और न ही कोई भारतीय अदालत किसी भारतीय नागरिक को अमेरिका में दावे सुलटाने से रोक सकती है.

8 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूसीसी और सरकार की याचिकाएं मंजूर कर लीं.

11 अक्तूबर: हाईकोर्ट ने यूसीसी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी.

13 अक्तूबर: हाईकोर्ट ने मामले को जिला जज की अदालत से वरिष्ठ अतिरिक्त जिला जज की अदालत में भेजने की यूसीसी की अपील मंजूर कर ली.

26 अक्तूबर: सरकार ने भोपाल मामले को जिला जज की अदालत से स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरोसेमंद, टिकाऊ व हर प्रकार से सुरक्षित छतों के लिये उपयुक्तः

गैल्वेनाइज़्ड चादरों की छतें.

अपनी अनगिनत खूबियों के कारण गैल्वेनाइज़्ड स्टील की चादरें हर प्रकार की छतों के लिये अन्य किसी सामान की तुलना में कहीं बेहतर हैं। चाहें कारखाना हो या गोदाम, बस स्टैन्ड हो या घर, सभी के लिये।

स्टील के ऊपर चढ़ी जिस्ते की परत इन्हें टिकाऊ बनाये, तथा हवा, पानी या बर्फ सभी से बेअसर भी बनाये।

छतें जो चिटके नहीं

ठोस स्टील से बनी गैल्वेनाइज़्ड स्टील की मजबूत चादरें न तो चिटके न ही उखड़ें। इसलिये आश्चर्य की कोई बात नहीं यदि आपको गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनी 100 वर्ष पुरानी छत दिखाई पड़ जाये।

छतें जो टपकें नहीं

गैल्वेनाइज़्ड चादरों से बनी छतें अन्य किसी सामान की तुलना में कभी टपकती नहीं हैं। चाहें कितनी ही घनघोर बारिश क्यों न हो। यानि कि बारिश के मौसम में पूर्ण राहत, और टपकती छतों से हमेशा के लिये छुटकारा.

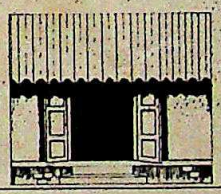

हल्की व किफ़ायती छतें

नवीनतम तकनीक से निर्मित गैल्वेनाइज़्ड स्टील की चादरें बेजोड़ मज़बूती के बावजूद अत्यन्त हल्की होती हैं। यही नहीं आधुनिक तकनीक.3 मि.मी. पतली चादरों को भी मोटी गेज की चादरों की भाँति मज़बूती प्रदान करती है। अतः इन्हें लगाना व इधर उधर ले जाना और लाना किफ़ायती व आसान है। इसके अलावा वज़न में हल्की होने के कारण गैल्वेनाइज़्ड स्टील की छतों को कम सहारे की आवश्यकता होती है। यानि आपके लिये बचत पर बचत।

स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ छतें

यदि गैल्वेनाइज़्ड स्टील चादरों की इन सभी खूबियों से आप सन्तुष्ट व प्रभावित हुए हैं तो इनका एक और गुण निश्चय ही आपका मन जीत लेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये छतें पूर्णतया सुरक्षित हैं। इनसे आपके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। छतों के लिये प्रयुक्त अन्य वस्तुओं के विपरीत इनसे हानिकारक रेशे नहीं झड़ते जो अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछिये। उसकी भी यही राय होगी।

इसीलिये गैल्वेनाइज़्ड चादरों की छतें लगवायें। मुसीबतों से छुटकारा पायें और चैन की बंसी बजायें।

गैल्वेनाइज्ड स्टील चादरों के बारे में अधिक जानकारी के लिये लिखें:

ऑल इंडिया कोटेड स्टील मैन्यूफैक्चरर्स असोसिएशन
पोस्ट बॉक्स नं. 4206, नई दिल्ली-110048

मेम्बर्सः

● भारत बर्ग लि. ● ऐसेम कोटेड स्टील्स (जे-के) लि. ● मुनक गल्वा शीट्स लि. ● नेशनल स्टील इंडस्ट्रीज़ लि. ● निपन डेनरो इस्पात लि. ● सिटा कोटेड स्टील्स लि. ● सुरेका कोटेड ट्यूब्स एन्ड शीट्स लि. ● उषा रेक्टिफ़ायर कॉर्पोरेशन (इन्डिया) लि.– गैल्वेनाइज़्ड स्टील डिवीज़न. ● उत्तम गल्वा स्टील्स लि.

गैल्वेनाइज्ड चादरों की छतें – जो जीवन भर साथ निभायें व स्वस्थ रखें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Mudra:D:AICSMA 3401

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकार को चुनौती दी, जिसका आखिरी फैसला अभी होना है.

कार्बाइड की ओर से वकालत कर रहे हैं जाने-माने वकील एफ.एस. नरीमन. जवाबी याचिकाओं में मौलिक मुद्दे उठाए गए हैं ताकि इस पीठ के फैसले से ही मामला सुलझ जाए. शायद इसीलिए भारत सरकार की ओर से जिरह करते हुए महाधिवक्ता के. परासरन ने अदालत से यूसीसी की ओर से यह आश्वासन पाने को कहा कि वह अदालत के फैसले का पालन करेगी. अदालत ने सुनवाई जारी रखते हुए इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. कार्बाइड भारतीय अदालतों के सामने सिर्फ इसीलिए पेश हो रही है क्योंकि जिस अमेरिकी अदालत में इसके पहले सरकार द्वारा 3 अरब डॉलर के मुआवजे के लिए याचिका दायर की गई थी, उसका आदेश ऐसा ही था. लेकिन अमेरिकी अदालत में भारतीय अदालतों के फैसलों को चुनौती देने से यूसीसी को कोई नहीं रोक सकता. एक मुख्य मुद्दा यह है कि मुआवजा दावा अगर मान लिया जाता है तो इतनी बड़ी रकम अमेरिका में यूसीसी की संपत्ति की कुर्की से ही मिल सकती है.

यूनियन कार्बाइड हादसे की जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करती. उसका मानना है कि हादसा संयंत्र के एक असंतुष्ट कर्मचारी की तोड़-फोड़ का नतीजा है और हकीकत में कारखाने का कामकाज वह नहीं बल्कि यूसीआईएल चलाती है. उसका तर्क है कि अंतरिम मुआवजे का आदेश देना 'अंतिम फैसले से पहले ही फैसला सुनाने' और सुनवाई पूरी होने के पहले ही दोषी ठहराने जैसी बात बनती है.

गैसपीड़ितों के मुआवजा दावों को दुरुस्त करने में सरकार की नाकामी भी कार्बाइड वाले मुकदमे के लिए महत्वपूर्ण है. यूसीसी प्रत्येक दावेदार को हुए नुकसान, उसके इलाज और उसकी जरूरतों का ब्यौरा अदालत में पेश करने की मांग करती है. सरकार का दावा है कि उसने जांच करने के लिए 320 डॉक्टरों को लगाया है और इस तरह 2,80,000 दस्तावेज तैयार हो चुके हैं.

लेकिन गैसपीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि सरकार के सारे प्रयास बेतरतीब और अपर्याप्त हैं. 1985 में सरकार के खिलाफ कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में राहत और पुनर्वास के प्रयासों की देखरेख करने के लिए एक दो-सदस्यीय समिति मुकर्रर की थी. इस समिति ने कुछ मौलिक सवाल उठाए हैं. दो गैरसरकारी सदस्यों की इस अल्पमत रिपोर्ट में तीन साल बाद भी मृतकों की शवपरीक्षा सुविधा की कमी, गैसपीड़ितों में जहर के असर पर शोध के अभाव, उनके इलाज के बारे में लगातार ऊहापोह, पुनर्वास योजनाओं के अभाव, और चिकित्सकीय रिकार्डों की लापरवाही भरी देखभाल वगैरह की चर्चा की गई है. यह रिपोर्ट आईसीएमआर के अध्ययनों को अवैज्ञानिक तक ठहराती है. एक नमूना सर्वेक्षण में तो मृत्यु दर को राष्ट्रीय औसत से भी कम और यूरोपीय औसतों के करीब बताया गया है. ऐसे घालमेलों का नतीजा हुआ कि भोपाल में अभी भी डॉक्टर दुविधा में हैं कि आखिर कैसा इलाज चलाया जाना चाहिए.

राकेश जैमिनी

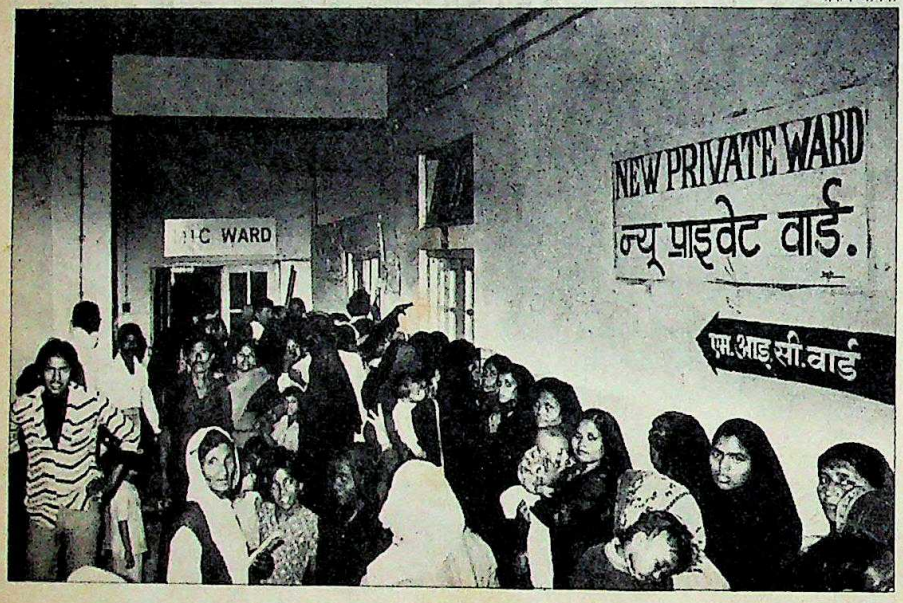

अभी भोपाल के डॉक्टर इलाज को लेकर दुविधा में हैं. भारी विवाद तो सायनाइड जहर की काट के लिए सोडियम थायोसल्फेट के प्रयोग पर है. कार्बाइड ने पहले तो इसके सिफारिश की पर बाद में पीछे हट गई

एक भारी विवाद तो सायनाइड के जहर की काट के लिए सोडियम थायोसल्फेट के प्रयोग पर ही है. पहले तो कार्बाइड ने इसकी सिफारिश की थी पर कुछ हफ्ते बाद ही इसे वापस ले लिया गया. तब तक आईसीएमआर ने भी इसकी सिफारिश की पर शर्त यह जोड़ी कि मरीज के पेशाब की जांच पहले कर ली जाए. चार साल बाद भी आईसीएमआर इस इलाज के प्रभावों पर कोई ठोस टिप्पणी नहीं जारी कर पाया है. सुप्रीम कोर्ट वाली समिति के अल्पमत सदस्यों में से एक, डॉ. अनिल सदगोपाल कहते हैं, "भोपाल में सरकार के कामकाज से हमारी निराशा को भोपाल के बाहर का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता." रिपोर्ट में राहत, चिकित्सकीय प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय चिकित्सा और पुनर्वास समिति के गठन की सिफारिश की गई है.

अदालत को इस सिफारिश पर अभी फैसला देना है. इस बीच वहां मुआवजे के मामले की सुनवाई चल रही है. फैसला जो भी हो पर भोपाल के अभागे गैसपीड़ितों के लिए फिलहाल आशा की कोई किरण भी नहीं नजर आ रही है. यदि अंतरिम मुआवजे की अदायगी के फैसले को कायम भी रखा जाता है तब भी इस बात की उम्मीद कम ही है कि यूसीसी इसकी फौरन अदायगी कर देगी. इसके लिए कंपनी की संपत्ति की खातिर अमेरिकी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे. गहरी काली सुरंग के पार जो दीप है उसकी रोशनी भी बहुत धुंधली नजर आती है.

—नरेंद्र कुमार सिंह, डेविड देवदास और न्यूयॉर्क में अमृत ककरिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Mutual-4711A/HN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह दुनिया भर में जाना-माना है

नाम है केल्विनेटर. एक रेफ्रिजरेटर जिस ने दुनिया भर में घर कर लिया है। 140 से अधिक देशों में सब से ठंडा होने के लिए विख्यात।

इसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करने वाला है इसका 'पावर-सेवर' कॉम्प्रेसर। यह शीघ्र ठंडा करता है तथा उस से भी शीघ्र बर्फ़ बनाता है, चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो। यह न्यूनतम बिजली की खपत करके अपनी ख्याति की कसौटी पर खरा उतरता है और वोल्टेज का कितना भी उतार चढ़ाव इसके कुशल कार्य में विघ्न नहीं डाल सकता।

इसमें वस्तुएं रखने की क्षमता से आप चकित रह जाएंगे। क्योंकि इसके कोने-किनारे-रहित विशिष्ट अन्दरूनी डिज़ाइन में अधिकतम स्थान का उपयोग हो सकता है।

सुदृढ़, पूर्णतः स्टील निर्माण तथा मज़बूत ए बी एस लाईनर, इसके बाहरी एवं अन्दरूनी भाग को अतिरिक्त मज़बूती तथा अधिक टिकाऊपन प्रदान करता है।

आपके चयन के लिए यह विभिन्न मॉडलों एवं आकर्षक रंगों में उपलब्ध है।

इसलिए खरीदिए दुनिया भर का मनपसन्द रेफ्रिजरेटर, केल्विनेटर।

विक्रय एवं सर्विस के लिए :

एक्स्पो मशीनरी लिमिटेड

प्रगति टावर, 26, राजिन्द्रा प्लेस
नई दिल्ली-110 008.

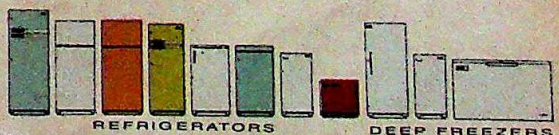

Mutual-4711A/HN

केल्विनेटर

रेफ्रिजरेटर

"इसकी ठण्डक ... बेमिसाल!"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब अपनी कलात्मक कल्पना का खूबसूरत फर्श सिर्फ 25% अतिरिक्त खर्च पर।

जे.के. व्हाइट सीमेन्ट यानि कम खर्च में शानदार फर्श

अपना घर बना रहे हैं तो सिर्फ चारदीवारी की सुन्दरता का मत सोचिये।

जे के व्हाइट सीमेन्ट इस्तेमाल कर, अपने घर के फर्श तक को खूबसूरत बनाइये।

बेमिसाल रंग और कल्पनातीत डिज़ाइनों वाले मनभावक फर्श बहुत ही कम खर्च में बन जाते हैं, जे के व्हाइट सीमेन्ट से।

10 फुट X 10फुट के साधारण फर्श और खूबसूरत फर्श को बनाने में खर्च की तुलना करके देखिये!

साधारण ग्रे सीमेन्ट	875/- रु.
जे के व्हाइट सीमेन्ट	1100/-रु.

केवल 225/- रु. के अतिरिक्त खर्च पर यह खूबसूरत मुनाफे का सौदा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्हाइट सीमेन्ट

जे के व्हाइट सीमेन्ट, दुनिया भर में व्हाइट सीमेन्ट के जाने-माने निर्माता, डेनमार्क के FL स्मिड्थ एण्ड कं. के तकनीकी सहयोग से बनाया जाता है। इसीलिये तो जे के व्हाइट सीमेन्ट बिना मिलावट वाला सबसे बेहतरीन व्हाइट सीमेन्ट कहलाता है। उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के कारण ही जे के व्हाइट सीमेन्ट भारत का सबसे अधिक बिकने वाला व्हाइट सीमेन्ट है।

आपके मनपसंद, हजारों तरह के रंग और डिज़ाइनों वाले फर्श बनाने के लिये यह असानी से – हर रंग, संगमरमर के पाउडर और चिप्स से घुल-मिल जाता है।

रंगों और डिज़ाइनों के लिये मुफ्त सलाह

जे के व्हाइट सीमेन्ट से बनाये जा सकने वाले बेशुमार रंगों और डिज़ाइनों वाले फर्श के बारे में आप "जे के व्हाइट सीमेन्ट फ्लोर डिज़ाइन प्लान" से मुफ्त में सलाह ले सकते हैं। आपके फर्श का बेमिसाल डिज़ाइन बनाने में हम आपकी मदद करेगें।

ये ही नहीं, जब आप मुफ्त सलाह योजना का लाभ उठायेगें तो आपको जे के व्हाइट सीमेन्ट की हर खरीद पर विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा।

आपके लिये अनोखे लाभ वाली यह विशिष्ट सुविधा खूबसूरत डिज़ाइन वाले फर्श के प्रणेता,सिर्फ जे के व्हाइट सीमेन्ट ने ही उपलब्ध करवाई है।

जे के व्हाइट सीमेन्ट का इस्तेमाल,
यानि फर्श पर सब देखें आपकी कल्पना का कमाल।

आज ही संलग्न कूपन भर कर हमें भेजें।

To: JK White Cement Floor Design Plan
Ashoka Estate, 8th Floor,
24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

I'm building my house and would like to know how 'JK White Cement Floor Design Plan' can help me to design my own floors.

Name _____

Address _____

Tel. No. _____

JK White Cement
India's largest selling white cement

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बनवाइये। वो भी साधारण ग्रे सीमेन्ट से

J.K. White Cement

FLOORS

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आपकी कल्पना उतर आयी फर्श पर, हमेशा-हमेशा के लिये

Available at Mill's SUMANGAL showrooms and other leading stores.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वो कौन जा रहा है, वी.आइ.पी. लेकर ?

हर वी.आइ.पी. बैग के बनाने में उसकी खूबसूरत शैली का पूरा ध्यान रखा जाता है.
सुन्दर रूपरेखा, उत्कृष्ट अन्दरूनी भाग, विशेषताओं में एकमात्र.
और म्यूटेड तथा मैटैलिक रंगों की चुनाव सुविधा.
जब वी.आइ.पी. आपके हाथ रहे.
हर नज़र इसी पे आ अटके.

VIP

लगेज जो आपके साथ जँचे

BELTEK

आधुनिकता का कमाल. बेलटेक टी.वी. बेमिसाल

बेलटेक 777. स्टाइलिंग में बेमिसाल. कार्यकक्षमता में बेमिसाल. गुणों में बेमिसाल.

BELTEK

BTK 777

बेलटेक 777. एक ऐसा कलर टी.वी. जो अभी तक देखने में नहीं आया. इसका डिज़ाइन कम्प्यूटरों द्वारा किया गया है ताकि किसी प्रकार का दोष न रहे. इसके प्राकृतिक रंग तथा मधुर आवाज़ आप पर जादू सा कर देंगे. एक प्रीमियम टी.वी. जो सचमुच अपने समय से बहुत आगे है.

विशेषताएं:

- बर्स्ट क्लीनिंग सर्केट: रंगों की अशुद्धियों को दूर करने हेतु
- ए.बी.सी.एल.: तनाव रहित टी.वी. देखने का आनन्द
- चैनल, वाल्यूम, कलर एवं ब्राइटनैस का स्क्रीन पर डिस्पले
- आटो सर्च टयूनिंग • सम्पूर्ण-क्रिया रिमोट कन्ट्रोल
- 3 स्पीकर सिस्टम

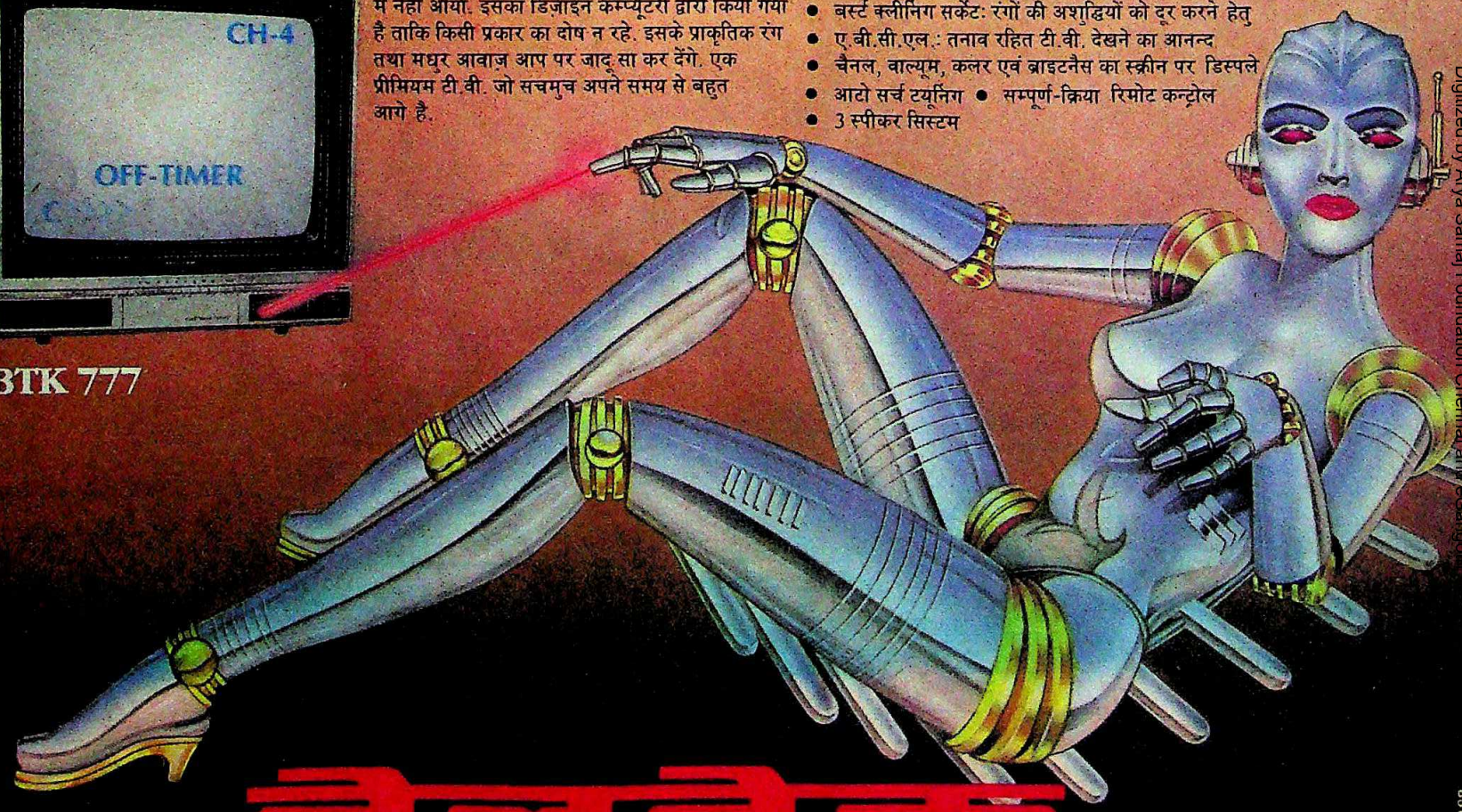

बेलटेक

शार्प फ़ोकस टी.वी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Corcom/BE/0188

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

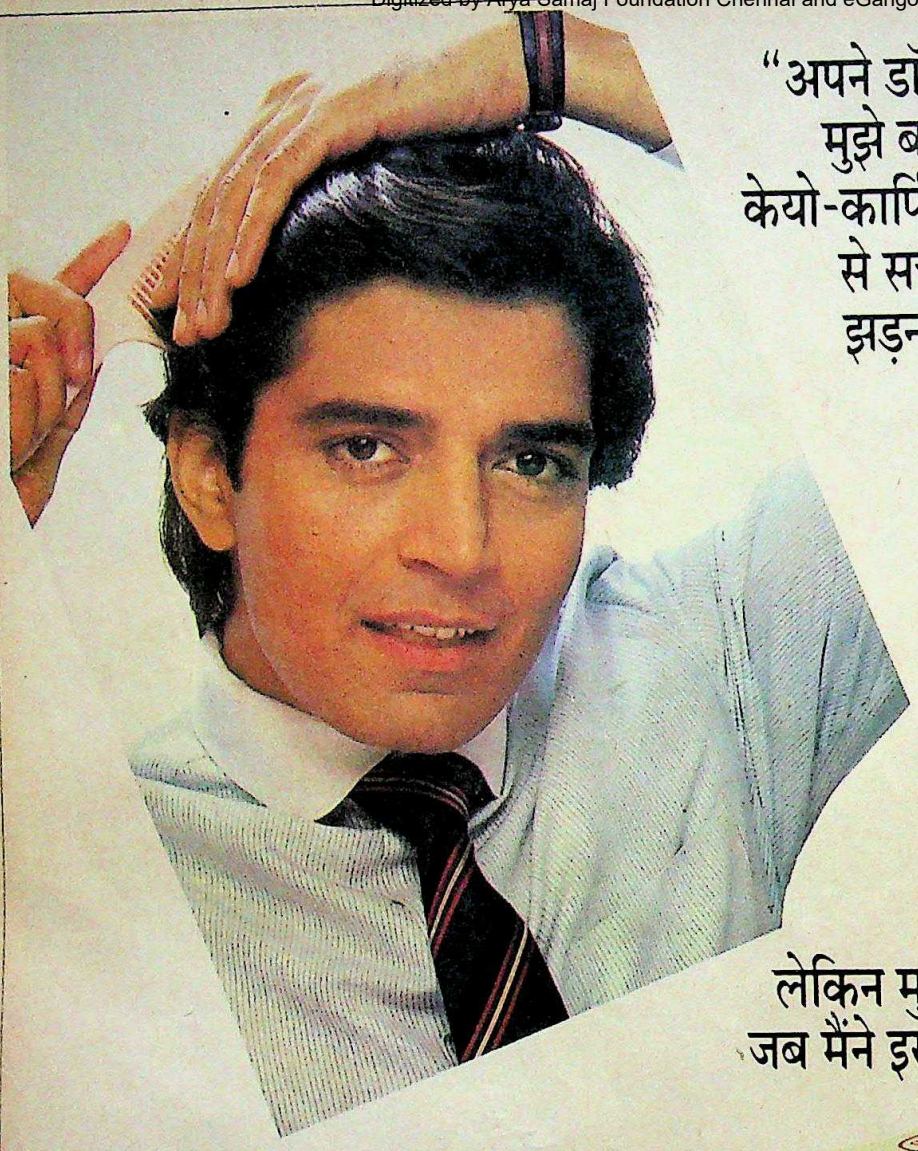

"अपने डॉक्टर से यह जानकर
मुझे बड़ी खुशी हुई कि
केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र
से सचमुच बालों का
झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ
जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्ज़ाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३%में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

बालों का झड़ना रोकने का
प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नौका को लेकर तोकझोंक

एक मामूली-सी प्रशासनिक चूक ने बिहार के राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह और मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बीच चले आ रहे विवाद को और तीखा कर दिया. पिछले पखवाड़े दोनों ने छठ उत्सव के मौके पर गंगा नदी में नौका बिहार का लुत्फ उठाने की सोची. इसके लिए दो मोटर लांच तैयार की गईं. लेकिन जब सिंह गंगा किनारे पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि मुख्यमंत्री की

कृष्ण मुरारी किशन

आजाद और सिंहः मुंह फुलौव्वल

सजी-धजी लांच के मुकाबले उनकी लांच न केवल फटीचर-सी है बल्कि उसे एक गंदी जगह पर भी खड़ा किया गया है.

राज्यपाल इस कदर क्षुब्ध हुए कि उन्होंने एक कड़ी चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से अपने सभी संबंध तोड़ डाले. राज्यपाल ने विमान द्वारा दिल्ली पहुंचकर पार्टी आलाकमान से अनुरोध किया कि या तो उन्हें राज्य से हटा लिया जाए या आजाद को.

दरअसल, गोविंद नारायण और आजाद के बीच झगड़ा कुछ महीने पहले सामने आया था जब राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी. चिट्ठी में कहा गया था कि, "मुख्यमंत्री के साथ बहस करना कुश्ती करने जैसा है...उन्हें राज्यपाल की कानूनी या संवैधानिक हैसियत के बारे में कुछ भी पता नहीं है. धमकी दिए बिना वे कुछ सुनते ही नहीं...मैं परेशान हूं...बताएं, मैं क्या करूं?"

इस मामले में भला राजीव क्या कहते!

स्वेच्छा से आत्मसमर्पण

पश्चिम बंगाल में आखिर एक कोना ऐसा भी है जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का सिक्का हरगिज नहीं चलता. दार्जिलिंग जिले में 13 दिसंबर को होने वाले पर्वतीय परिषद के चुनाव की तैयारियों से तो यही लगता है. इस क्षेत्र में गोरखा मुक्ति मोर्चे की पकड़ इतनी मजबूत है कि माकपा खुशी-खुशी पर्वतीय परिषद पर मोर्चे का वर्चस्व मान लेने को तैयार दिखती है.

वैसे मुख्यमंत्री ज्योति बसु दो साल में पहली बार अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए दार्जिलिंग का दौरा करने वाले हैं. लेकिन माकपा ने गोरखा मोर्चे को सीधी मुठभेड़ के लिए उकसाकर कोई खतरा मोल न लेने का फैसला किया है. लगता है पार्टी ने गोरखा मोर्चे के 26 महीने चले आंदोलन से कड़वा सबक सीखा है. तब पर्वतीय क्षेत्र से उसके कार्यकर्ताओं का वस्तुतः सफाया कर दिया गया था. एक माकपा नेता के अनुसार, "हम वही सब करेंगे जो इंका ने पंजाब समझौते पर दस्तखत करने के बाद वहां किया था." उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके परिणाम पंजाब समझौते जितने घातक नहीं होंगे.

अब प्रकृति का भी प्रकोप

मानो आतंकवादियों द्वारा मचाई जा रही तबाही ही काफी नहीं थी. लुधियाना की कभी फल-फूल रही औद्योगिक इकाइयों पर अब प्रकृति ने भी कहर बरपा किया है. दो महीने पहले आई अभूतपूर्व बाढ़ ने यहां की करीब 200 इकाइयों को लपेट में ले लिया. इनमें 50 तो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं.

बाढ़ से प्रभावित 150 इकाइयों के मालिकों का शुरुआती अनुमान है कि उनका करीब 32 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है. इन इकाइयों में अभी काम चालू न होने के कारण बहुत से लोगों को अंदेशा है कि करीब दो लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे जिससे आतंकवाद को बल मिल सकता है. इसके अलावा इन इकाइयों के मालिकों द्वारा मूल्यांकन समिति को दिए ज्ञापन के अनुसार इनमें कई इकाइयां तो निर्यात भी करती थीं और उनके बंद होने से हर माह करीब तीन करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा.

बाढ़ से प्रभावित उद्योगपतियों की अनेक मांगें— मसलन, लुधियाना नगर निगम पांच साल के लिए सभी कर माफ कर दे— हालांकि व्यावहारिक नहीं लगती लेकिन इसमें शक नहीं कि इस मौके पर दी गई सहायता से सरकार को अपनी छवि निखारने में मदद जरूर मिल सकती है.

अंधेरे में तीरंदाजी

मोरवी में हुए बम विस्फोट में एक परिवार के आठ सदस्यों की मौत के तीन हफ्ते बाद भी गुजरात पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है. विस्फोट हालांकि शहर के बीचोबीच एक थाने के नजदीक हुआ था पर इस हादसे का न कोई चश्मदीद गवाह है, न प्रभावित कोई व्यक्ति ही जिंदा बचा है. गुजरात पुलिस के उप-महानिरीक्षक आर.एन. भट्टाचार्य भी कबूल करते हैं कि "यह काम भूसे के ढेर में सुई तलाशने जितना ही कठिन है."

उनकी निराशा वाजिब भी है. पिछले 16 महीनों में सौराष्ट्र क्षेत्र में यह इस किस्म की चौथी वारदात है. इनमें 28 लोगों की जाने जा चुकी हैं. पहला विस्फोट जुलाई 1987 में बांकानेर में हुआ था, जिसमें एक पूर्व विधायक मंजूर हुसैन पीरजादा और चार दूसरे

बम विस्फोट वाली जगहः सबूत का अभाव

लोग मारे गए थे. सबूतों के अभाव में यह मामला दाखिर दफ्तर कर दिया गया था. स्थानीय पुलिस इस कदर हतप्रभ थी कि मोरवी में हुए विस्फोट के एक दिन बाद ही घटनास्थल पर वडोदरा और अहमदाबाद के जासूस आ पहुंचे. उनकी रिपोर्ट से यह पुष्टि हो गई कि इस विस्फोट में भी पहले जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था. सभी हादसों में कई समानताएं होने के बावजूद अपराधियों को पकड़ने के कोई सूत्र नहीं दिख रहे. हारकर सरकार ने जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केरल

मोर्चे को कई मोर्चों पर चुनौती

माकपा के नेतृत्व वाली केरल की वाम मोर्चा सरकार गंभीर मुश्किलों में फंस गई है. कुछ मुश्किलें उसे पुरानी सरकार से 'उपहार' मिली हैं और कुछ उसने खुद पैदा की हैं. कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, वित्तीय संकट गहरा रहा है और इंका के नेतृत्व में विपक्षी दलों के तेवर तीखे हो रहे हैं. विशेष संवाददाता श्रीधर पिल्लै ने इस स्थिति का लेखा-जोखा तैयार किया.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की अगुआई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को राज्य की बागडोर संभाले हुए 19 महीने बीत गए हैं. लेकिन अभी भी उसकी गाड़ी जैसे घिसट ही रही है, गति पकड़ती नहीं दिख रही. ई.के. नयनार सरकार के सामने कई समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं—कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, बेरोजगारी और बढ़ता जन असंतोष.

लेकिन नयनार के लिए ये सारी बातें कोई नई नहीं हैं. उनकी पिछली सरकार मात्र 21 महीने बाद ही अक्तूबर 1981 में गिर गई थी. पर इस बार पांच साल तक चले इंकाई कुशासन के बाद सत्ता संभालने पर उनसे उम्मीद थी कि उनकी छवि बेहतर होगी. लेकिन सचाई यह है कि वाम मोर्चा अभी भी पूरी तरह ऊहापोह में दिखता है. उधर, इंका के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा अपने हथियारों पर सान चढाता जा रहा है.

केरल के मतदाताओं ने नयनार और वाम मोर्चा को इस उम्मीद से दूसरा मौका दिया कि इससे इंका के भ्रष्ट और सांप्रदायिक शासन का खात्मा होगा. लेकिन नयनार के लिए फिर पुरानी बीमारी जैसे उभर आई है. 1981 में उनकी सरकार कानून-व्यवस्था की बदतर हालत के कारण गिरी थी. इस बार भी यह समस्या उनके लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है. पिछले महीने मालाबार इलाके में कानून व व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर नयनार के पूर्व सह-योगियों कांग्रेस (स) और केरल कांग्रेस (मणि गुट) ने उनकी जमकर खिंचाई की. वहां भारतीय मुस्लिम लीग और माकपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों में कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई.

अभी महीने भर पहले ही माकपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ समझौता किया है. मार्च '87 से लेकर अगस्त '88 के बीच दोनों संगठनों के बीच करीब 500 झड़पें हुई थीं.

हिंसा की ताजा वारदात कालिकट से करीब 60 किमी उत्तर नादपुरम में हुई. इस इलाके में मुस्लिम लीग के एक जुलूस ने खेतिहर मजदूरों के नेता व माकपा के ताकतवर विधायक ए. कनारन की गाड़ी पर हमला कर दिया, इस पर माकपा कार्यकर्ताओं ने लीग समर्थकों पर जवाबी हमला किया. विरोध में कालिकट में लीग ने जुलूस निकाला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

इन झड़पों से स्थिति और गंभीर हो गई. कालिकट, मलप्पुरम और कन्नानूर जिलों में कई दिनों तक तो मानो पूरी अराजकता ही रही. विपक्षी नेता के. करुणाकरन ने सीआरपी को तैनात करने की मांग की. मगर वाम मोर्चा सरकार लाठीचार्ज को जायज ठहराती रही. और, नयनार की इस लापरवाही भरी टिप्पणी ने तो खुद उनकी पार्टी के लोगों सहित सबको नाराज कर दिया कि "यदि पुलिसवालों पर पत्थर फेंके जाएंगे तो वे जवाब में पत्थर फेंकेंगे ही."

मुस्लिम लीग ने लाठीचार्ज और मस्जिदों को अपवित्र करने की न्यायिक जांच की मांग की पर माकपा नेताओं ने कोई कार्रवाई नहीं की. तब वाम मोर्चा के ही नादपुरम के विधायक सत्येन मोकेरी ने इस मसले पर भूख हड़ताल करने की धमकी दे दी. आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा.

इस तरह माकपा नेतृत्व को न सिर्फ अपने ही कार्यकर्ताओं से परेशानी का सामना करना पड़ा बल्कि अपने ही पार्टी मुख्यालय एकेजी सेंटर से भी उसकी खिंचाई हुई. मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इसी मुख्यालय के इशारे पर काम करते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और इंकाई नेता ए.के. एंथनी ने कहा, "यह सरकार तो एकेजी सेंटर की कठपुतली है."

सरकार कठपुतली हो या नहीं, पर राज्य की राजधानी में यह आम धारणा है कि सरकार का बजट एक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री ने तैयार किया है. दरअसल, सरकार की परेशानी इन अफवाहों के कारण भी बढ़ गई है कि वित्तमंत्री तो बस दिखावटी ही हैं. फिर, आईएएस समेत 35 बड़े अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई ने अफसरशाही को भी नाराज कर दिया है. एक बड़े अधिकारी ने शिकायत की, "हमारी खुफियागीरी करने के लिए चपरासियों को लगा दिया जाता है. महत्वपूर्ण फाइलें मंजूरी के लिए एकेजी सेंटर पहुंच जाती हैं."

इसके अलावा, अपने प्रभावकारी घोषणापत्र के बावजूद वाम मोर्चा सरकार औद्योगिक नीति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं तैयार कर पाई है, हालांकि उसने नई पहल करने का दावा किया था. बहरहाल, स्थिति यह है कि देश के दूसरे हिस्सों में औद्योगीकरण में तेजी के बावजूद इस राज्य में सरकार एक भी बड़ा या छोटा उद्योग लगवाने में नाकाम रही है. बल्कि उलटे राज्य से उद्योग और पूंजी का पलायन खासकर पड़ोस के तमिलनाडु में हो रहा है. तमिलनाडु में उन्हें बेहतर कर दरें और औद्योगिक वातावरण मिलता है. इस पलायन में राज्य के मंत्री बेबी जॉन का बेटा भी शामिल है. वाम मोर्चा नारियल के रेशे और काजू उद्योगों में कार्यरत अपने मजदूर संघों पर भी काबू रखने में नाकाम रहा है. ये संघ उद्योगों में आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं.

लेकिन राज्य की उद्योगमंत्री के.आर. गौरी राज्य में औद्योगिक मोर्चे पर गतिरोध के लिए केंद्र और उसके पक्षपातपूर्ण रवैये को दोषी ठहराती हैं. वे राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने और उत्पादन बढ़ाने के उपायों की गिनती करती हैं. इस प्रभावशाली फेहरिस्त में कालिकट के निकट मावूर में बिड़ला रेयन प्लांट की शुरुआत, 711 बीमार इकाइयों को चालू करना और

पूंजी का पलायन तेजी से तमिलनाडु में हो रहा है. वहां कर की दरें कम हैं और बेहतर औद्योगिक वातावरण मिलता है

महिलाओं के लिए 182 उद्योगों को खोलना शामिल है.

उधर, इंकाई नेता मावूर समझौते को बिड़ला के हाथ में खेलने जैसा बताते हैं. उनका तर्क है कि सरकार कर्नाटक से 800 रु. प्रति टन के हिसाब से मिलने वाली लकड़ी इस प्लांट को 250 रु. प्रति टन पर बेचने को तैयार है. लेकिन केंद्र के पक्षपातपूर्ण रवैये से संबंधित गौरी का आरोप निराधार नहीं है. संसाधनों की खासी कमी हो गई है. वित्तमंत्री विश्वनाथ मेनन कहते हैं, "मेरा मुख्य काम केंद्र के बकाये के लिए रकम जुटाना रह गया है. पिछले साल हमें कर्ज और सूद के एवज में 200 करोड़ रु. अदा करना था. इस साल यह रकम 290 करोड़ रु. है."

पेचीदे वित्त विभाग को संभालने वाले वे पिछले 30 साल में पहले मार्क्सवादी मंत्री हैं. हालांकि उन्हें पार्टी महासचिव ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद के बेटे श्रीधरन नंबूदिरिपाद के रूप में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट का सहयोग प्राप्त है. श्रीधरन की भी राय यही है कि अर्द्ध विकसित अर्थतंत्र होने के कारण प्रमुख समस्या संसाधनों की कमी ही है.

यदि मार्क्सवादी नेतृत्व ने अपना पूरा ध्यान इस पेचीदा स्थिति से निकलने में लगाया होता तो कुछ सार्थक उपलब्धि हो पाती. पर सत्ताधारी वाम मोर्चे की प्रमुख सहयोगी माकपा तो भाकपा के चार मंत्रियों के पर कतरने में ही लगी है. ये मंत्री इन अड़चनों के बावजूद अच्छा काम कर रहे हैं. यहां तक कि वरिष्ठ नेता बेबी जॉन से भी इतना रूखा बरताव किया गया कि वे दफ्तर भी यदाकदा ही जाते हैं. वे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी विवादों को सुलझाने के लिए कलकत्ता में हैं. मार्क्सवादी अपने छोटे सहयोगियों के साथ भी वही नुस्खा अपना रहे हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ अपनाती रही है. यह नुस्खा है पैसों की सहायता में कमी करने का.

वैसे, यह कमजोर मार्क्सवादी सरकार भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब रही है. वह करुणाकरन सरकार के दो मंत्रियों— यू.ए. बीरन और बालकृष्ण पिल्लै— पर मुकदमा चलाने में कामयाब रही है. ये दोनों पूर्व मंत्री क्रमशः चावल के सौदे और उदयमंगलम बांध में दरार के घोटालों में फंसे थे. लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यह विजय खोखली ही लगती है. एक व्यापारी ने कहा, "पूरा औद्योगिक क्षेत्र पंगु

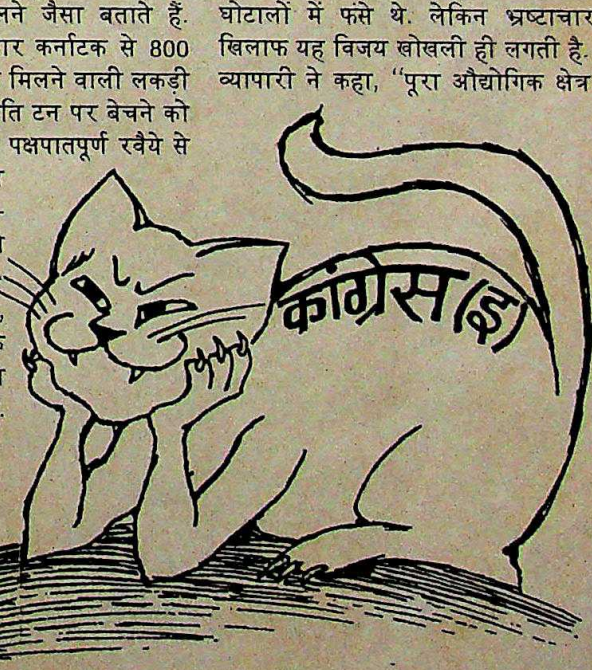

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हो गया है क्योंकि पूरा प्रशासन ठप है. करुणाकरन के जमाने में फाइलें आगे तो बढ़ती थीं, भले ही कीमत देनी पड़ती थी."

आखिरकार माकपा की आंख खुलती-सी लग रही है. माकपा के प्रभावशाली सचिव वी.एस. अच्युतानंदन ने माना कि माकपा पुरानी गलतियों को निश्चित तौर पर सुधारने की कोशिश कर रही है और अपने रिकार्ड को दुरुस्त करने की कोशिश करेगी.

लेकिन वायलार रवि और करुणाकरन सरीखे विरोधी नेता इससे कतई सहमत नहीं हैं. करुणाकरन कहते हैं, "वे जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे जबकि राज्य में प्रशासन लगभग ठप है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है." इसमें कुछ हद तक सचाई भी है. 19 सदस्यीय नयनार मंत्रिमंडल के कम-से-कम 11 मंत्रियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे अस्पताल में हैं. इससे पार्टी की परेशानी खत्म होती नहीं दिखती. इसके लिए पार्टी में नौजवानों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसका जबरदस्त अभाव है. पार्टी और सरकार को इंका के बढ़ रहे आंदोलनों से भी जूझना है.

ऐसे नाजुक मोड़ पर पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि कानून व व्यवस्था की समस्या उभरे. माकपा कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवकों की लंबी होती कतार पर काबू पाने में नाकामी, और उसकी कमजोरी का लाभ उठाने की ताक में बैठे विपक्ष से निबटने के लिए नयनार को रणनीतिक कौशल और आर्थिक विशेषज्ञता दिखानी होगी. इसके अलावा कोई चारा नहीं. नादपुरम की वारदात छोटी भले हो पर यह उनकी सरकार को हिला सकती है. यानी साफ है कि पुलिस को ईंट का जवाब ईंट से देने की इजाजत देने की छूट वे नहीं ले सकते.

ई.के. नयनार

'केंद्र ही दोषी'

अपने दूसरे कार्यकाल के 20 महीने बाद भी 69 वर्षीय मुख्यमंत्री ई.के. नयनार राज्य की प्रमुख परेशानियों पर काबू नहीं पा सके हैं. त्रिवेंद्रम सचिवालय के अपने दफ्तर में 'इंडिया टुडे' से घंटे भर की बातचीत में मिलनसार नयनार ने अपनी सरकार का पक्ष रखा. कुछ अंश :

श्याम टेकवानी

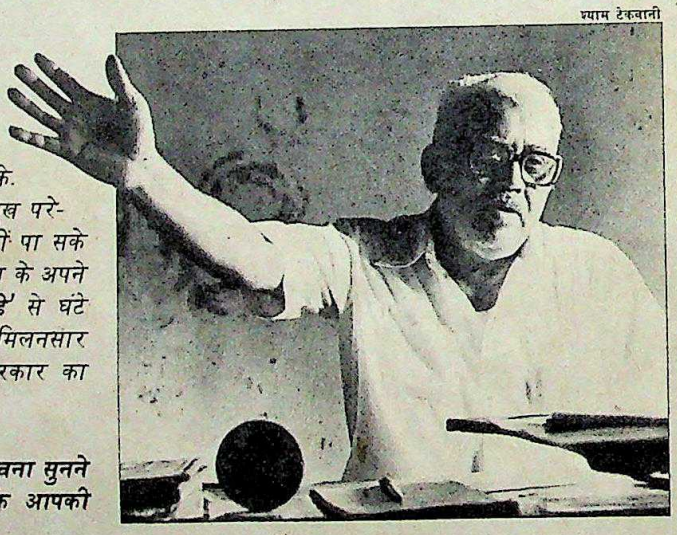

• हर तरफ आलोचना सुनने को मिल रही है कि आपकी सरकार निक्कमी है.

मेरा ख्याल है कि भारी वित्तीय संकट और केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये के बावजूद हमने काफी अच्छा काम कर दिखाया. पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंध की वजह से हमारे पास विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है. 1982 में जब करुणाकरन सरकार सत्ता में आई तो राज्य पर 1,113 करोड़ रु. कर्ज था. पर उनकी सरकार गिरने के वक्त यह कर्ज 2,779 करोड़ रु. तक हो गया. संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार तो केंद्र की आर्थिक मदद के सहारे टिकी थी. लेकिन वाम मोर्चा के सत्ता में आते ही हालात में भारी तब्दीली आई. पहले तो भयंकर सूखा पड़ा और फिर जब हमने 600 करोड़ रु. की अनुदान राशि दिए जाने का अनुरोध किया तो हमें महज 10 करोड़ रु. थमा दिए गए. हम अभी भी पिछली सरकार के कर्ज की भरपाई कर रहे हैं.

• आपने बिड़ला की मावूर पल्प फैक्टरी को दुबारा शुरू करने के सिवा औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया?

फिलहाल राज्य का औद्योगिक माहौल शांतिपूर्ण है. हमने अनेक फैक्टरियां दुबारा खुलवाने और बीमार इकाइयों को व्यवस्थित करने के अलावा काजू और जूट सरीखे पारंपरिक उद्योगों को भी बढ़ावा दिया है. लेकिन सबसे बड़ा काम तो बिड़ला की मावूर पल्प फैक्टरी दुबारा खुलवाने का रहा. चुनाव में हमने यह प्रमुख वायदा किया था. करुणाकरन सरकार यह काम नहीं कर पाई थी.

• लोगों का मानना है कि आप अपनी सभी खामियों का जिम्मेदार केंद्र को ही ठहराते हैं.

केंद्र ने केरल की उपेक्षा की ही है. वायदा की गई परियोजनाएं भी केरल के बजाय दूसरे राज्यों को दे दी जाती हैं. केंद्र की आयात-निर्यात नीतियां तो खासकर केरल की नकदी फसलों के लिए नुकसानदेह रही हैं. केरल में केंद्र का निवेश भी घट गया है. 1974 में यह 3.28 फीसदी था और 1987 में 1.58 फीसदी रह गया.

• क्या त्रिवेंद्रम के माकपा मुख्यालय (एकेजी केंद्र) में समानांतर सचिवालय चल रहा है?

एकेजी केंद्र के नेताओं ने सरकार के काम में कभी दखल नहीं दिया. हां, केंद्र पार्टी के मस्तिष्क का काम जरूर करता है.

• राज्य में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, विपक्ष के इस आरोप के बारे में आपको क्या कहना है?

1957 में जब कम्युनिस्ट केरल में पहली बार सत्ता में आए, तब से कांग्रेस कानून और व्यवस्था का हौवा खड़ा करती आ रही है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और माकपा के बीच झड़पें इसलिए होती आ रही हैं क्योंकि संघ मूल रूप से कम्युनिस्ट विरोधी है. इंका तो उसका इस्तेमाल मुस्लिम लीग सरीखी दूसरी सांप्रदायिक पार्टियों की तरह करती है.

• आपके आलोचकों का दावा है कि आपकी सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में सभी बड़े नीतिगत फैसले वापस ले लिए.

हां. हमने कई फैसले बदले हैं और लोगों ने चाहा तो हम भविष्य में भी ऐसा ही कर सकते हैं.

• अफवाह है कि आपकी साझा सरकार के भागीदार खासकर आरएसपी और उसके नेता बेबी जॉन माकपा की भूमिका से बहुत खुश नहीं हैं.

बेबी जॉन जतिन चक्रवर्ती नहीं हैं. वाम मोर्चे को कोई नहीं छोड़ेगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कब्जा टालने की कोशिश

गैमन इंडिया के प्रबंधक अपनी कंपनी पर मनोहर और किशोर छाबरिया का कब्जा टालने के लिए क्या किसी 'संकटमोचन' की तलाश में हैं? माना जा रहा है कि 100 करोड़ रु. कारोबार वाली इस निर्माण कंपनी के प्रबंध निदेशक टी.एन. सुब्बाराव एक 'मित्र' कंपनी से अपने शेयर खरीदने का आग्रह करने पर विचार कर रहे हैं. छाबरिया बंधुओं ने ब्रिटेन में गैमन परिवार की एक शाखा और भारतीय बाजार से शेयर खरीदकर कंपनी में अपने शेयरों की स्थिति काफी मजबूत (28 फीसदी से अधिक) बना ली है. लेकिन उन्होंने शेयर अपने नाम करने की कोई कोशिश अब तक नहीं की है. प्रबंधकों के पास 10 फीसदी शेयर हैं और शेयर होल्डरों की पिछली बैठक में उन्होंने 41 फीसदी शेयरों के मालिकों को अपने पक्ष में कर लिया था. कंपनी के अधिकांश शेयर आम लोगों के पास ही हैं इसलिए उन्हें अपने पक्ष में करने की लड़ाई के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता.

नई दोस्ती, नई व्यवस्था

सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और उम्मीद है कि यह दोस्ती नए (वित्तीय) गुल खिलाएगी. दोनों बैंक अब कई और संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं. इनमें फोन पर ही देसी और विदेशी लेन-देन और संयुक्त ट्रैवलर चेक जारी करना शामिल है. सहमतिपत्र पर तो कुछ महीने पहले दस्तखत हो गए थे लेकिन दूसरे फैसले अब तक नहीं हुए हैं.

उलझती-सुलझती गुत्थी

बिड़ला समूह की पुनर्गठन की योजना समस्याओं के झंझावात में फंस गई लगती है. बिड़ला की कुछ कंपनियों के शेयरों में हो रही उठापटक से तो यही नजर आता है. के. के. बिड़ला की दो कंपनियों—टैक्समॅको और इंडिया स्टीमशिप के शेयर कलकत्ता में चढ़ गए. पर्यवेक्षकों की राय में जानबूझकर की गई खरीद के कारण ऐसा हुआ. पर बीमार चल रही इंडियन स्टीमशिप के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी एकाएक क्यों कर बढ़ गई? इसमें एक और गुत्थी भी है. यानी एक-दूसरे की कंपनियों में हिस्सेदारी के मामले के निबटारे को लेकर एस.के. बिड़ला और आदित्य बिड़ला में चल रहे मतभेद. आदित्य बिड़ला समूह की बढ़िया कामकाज करने वाली कंपनियों में एस.के. बिड़ला के काफी शेयर हैं. इसीलिए दोनों के बीच हाल ही में इन शेयरों की बदली पर सहमति तो हो गई लेकिन जानकार सूत्रों के मुताबिक एस.के. बिड़ला द्वारा ऑफर की गई कीमत को लेकर झंझट हो गया है. इसलिए बातचीत का एक और दौर जल्द ही शुरू होने वाला है.

फ्रांसीसी सहयोग की उम्मीद

इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र दुलहस्ती पनबिजलीघर बनाने के लिए सीजीईई एथसॉम के साथ समझौता कर लेगा. यह परियोजना विवादों से घिरी हुई है. सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लगने वाले इस बिजलीघर के लिए फ्रांसीसी कंपनी एथसॉम को अनुमतिपत्र दे दिया था. लेकिन कंपनी ने बाद में मांगें बढ़ा दी. इनमें आयकर में छूट और आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क न लगाने की मांग भी थी. इसलिए इस करार पर दस्तखत होने में देरी हो गई. अब मतभेद समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं. अगर सफलता मिली तो फरवरी से पहले करार हो जाएगा. तभी फ्रांस के राष्ट्रपति मितरां भारत आ रहे हैं.

स्पर्धा से घटा मुनाफा

हालांकि सरकार विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दे रही है लेकिन कुछ परेशानी भरी खबरें भी मिल रही हैं. विदेशी कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनियों में मुनाफे की दर गिर रही है. एक सरकारी प्रकाशन के अनुसार ऐसी 71 कंपनियों के मुनाफे में 1986-87 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 15.05

चार्ट: बी.के. शर्मा

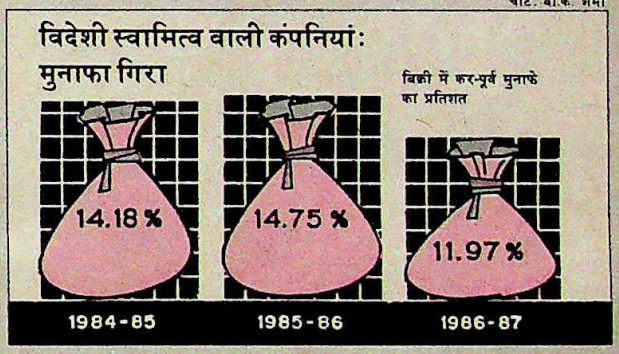

फीसदी कमी हुई. बिक्री में मुनाफे का प्रतिशत भी तीन वर्षों में कम हुआ है (देखें तालिका). यहां यह बात उल्लेखनीय है कि इन विदेशी कंपनियों की बिक्री और संपत्तियों में वृद्धि हुई है. मुनाफे में गिरावट के कारण स्पष्ट नहीं हैं. लेकिन बाजार में बढ़ी प्रतिद्वंद्विता उनकी इस मंदी का एक कारण हो सकता है.

बंटवारे की बातचीत

मोदी परिवार के दो धड़े आखिरकार अपने 1100 करोड़ रु. के औद्योगिक साम्राज्य के बंटवारे की बातचीत शुरू कर रहे हैं. लगता है समूह की कई कंपनियों के बंटवारे पर तो सहमति हो गई है पर मोदीपोन का मसला अटका हुआ है. उधर 23 नवंबर को मोदी रबर के प्रबंधक मंडल की बैठक में वित्तीय संस्थानों ने साफ कहा कि पारिवारिक लड़ाई अब हद से आगे बढ़ चुकी है. छह स्वतंत्र निदेशकों का इस्तीफा लेने के बाद अब प्रबंधक मंडल में वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का बहुमत हो गया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी रबर के अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करने का जो फैसला दिया उसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि वित्तीय संस्थाएं कभी भी अध्यक्ष बदल सकती हैं (उनके पास 51 फीसदी शेयर हैं). स्पष्ट है कि मोदी समूह के प्रमुख केदारनाथ मोदी अध्यक्ष पद पर वित्तीय संस्थाओं की मर्जी से ही बने हुए हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डीसीएम

बंटवारे की उत्सुकता आखिर रंग लाई

घाटे में फंसा यह समूह तीन हिस्सों में बंटा

अध्यक्ष बंसीधर को अभी ढेर सारी सफाई देनी है. 23 दिसंबर को डीसीएम शेयरधारकों की सालाना बैठक में वे शायद बताएंगे कि डीसीएम को तीन अलग-अलग कंपनियों में बांट देने से उन्हें क्या फायदा होगा; अभी तो किसी एक डिवीजन का मुनाफा दूसरे के घाटे के कारण मारा जाता है, जबकि तीन कंपनियां बना देने से वे ज्यादा तेजी से विकास कर पाएंगी.

पिछले महीने के शुरू में अध्यक्ष बंसीधर, प्रबंध निदेशक विनय भरतराम और उप प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ श्रीराम ने 624 करोड़ रु. कारोबार वाली डीसीएम को तीन हिस्सों में बांटने संबंधी दस्तावेज पर दस्तखत किए थे (देखें चार्ट). पिछले पखवाड़े के अंत में डीसीएम बोर्ड की बैठक ने इस फैसले का अनुमोदन करते हुए प्रबंध निदेशकों से तीन कंपनियों की संभावनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा. एक बयान में प्रबंधकों ने कहा कि डीसीएम शेयरधारकों को तीनों कंपनियों में शेयर दिए जाएंगे.

इन नाटकीय घटनाओं से लगता है कि श्रीराम परिवार में बरसों से चले आ रहे गंभीर मतभेद अब सुलट गए हैं और मुसीबत में फंसा यह समूह घाटे से उबरने वाला है. करीब एक दशक पहले डीसीएम 10 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों की सूची में चौथे स्थान पर था. लेकिन पिछले साल हिसाब-किताब के तरीके में बदलाव की वजह से उसे 22 करोड़ रु. घाटा उठाना पड़ा. इससे शायद वह अगले कुछ वर्षों तक लाभांश न दे पाए.

समझौते के मुताबिक बंसीधर को कोटा स्थित उर्वरक, सीमेंट और रासायनिक इंकाइयां मिली हैं. यह कांप्लेक्स एक वक्त इतने घाटे में चला गया था कि इसकी नीलामी की नौबत आ गई थी. लेकिन अब इसके उत्पादों की बढ़ती मांग से उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसका मुनाफा 20 करोड़ रु. हो जाएगा. दूसरी ओर, बंसीधर के ही पास स्वंतत्र भारत मिल्स है जो हर महीने करीब 30 लाख रु. का घाटा उठा रही है.

चरतराम परिवार जय इंजीनियरिंग और उषा सेल्स सरीखी कंपनियों को चलाता रहेगा. उसे दिल्ली की श्रीराम फूड्स ऐंड फर्टिलाइजर्स और एक चीनी मिल भी मिलेगी.

भरतराम परिवार को मुनाफा कमा रही श्रीराम फाइबर्स (एसआरएफ) के अलावा डीसीएम टोयोटा (जिसकी बाजार में हालत पतली है) और घाटा दे रही दो इकाइयां—डीसीएम डाटा प्रोडक्ट्स और दिल्ली की डीसीएम टेक्सटाइल मिल (जिसके बंद होने का मामला अदालत में है) मिलेंगी.

बंसीधर को तकरीबन आधी संपत्ति मिली है...
कोटा कांप्लेक्स
(उर्वरक, पीवीसी, रेयन टायर कोर्ड, सीमेंट)
स्वतंत्र भारत मिल्स
दौराला शुगर वर्क्स

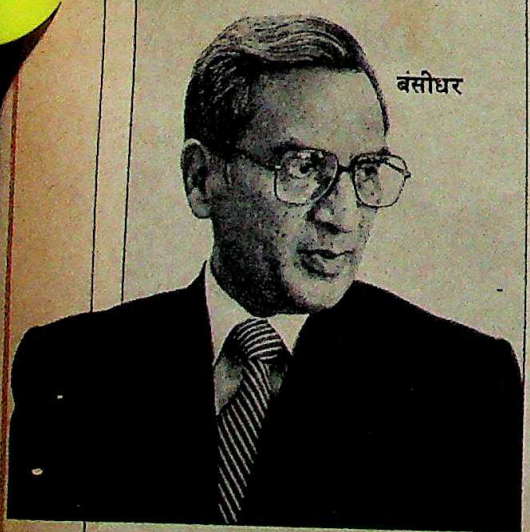
बंसीधर

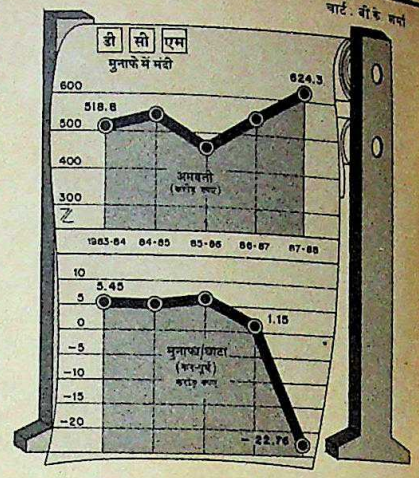

चार्ट : बी के वर्मा

डीसीएम डाटा प्रोडक्टस का जहां आधुनिकीकरण किया जा रहा है, वहीं सरकार ने अगर डीसीएम कपड़ा मिल की विवादास्पद योजना को हरी झंडी दे दी तो उसकी जमीन के विकास से मिलने वाला पैसा भी भरतराम परिवार की जेब में जाएगा.

एक वित्तीय संस्थान के प्रमुख ने नए समझौते को वित्तीय संस्थाओं द्वारा डीसीएम पर वित्तीय संकट से उबरने के लिए डाले गए दबाव का नतीजा बताया. एक वित्तीय दैनिक ने यहां तक लिखा कि भरतराम परिवार ने

चरतराम परिवार के पास मुनाफे वाली इकाइयां रहेंगी
श्रीराम फूड्स ऐंड फर्टिलाइजर्स
(वनस्पति, रसायन)
मवाना शुगर वर्क्स
जय इंजीनियरिंग वर्क्स
उषा सेल्स इंटरनेशनल
श्रीराम रेफ्रिजरेशन

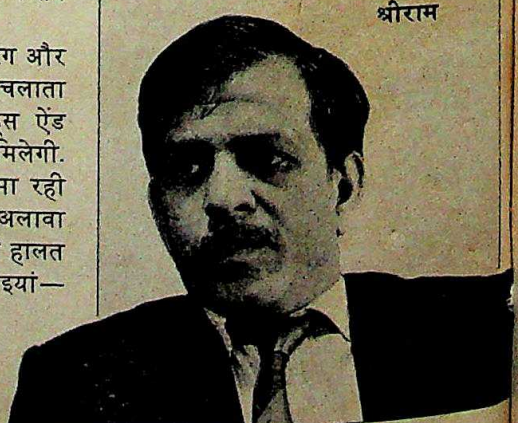
सिद्धार्थ श्रीराम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

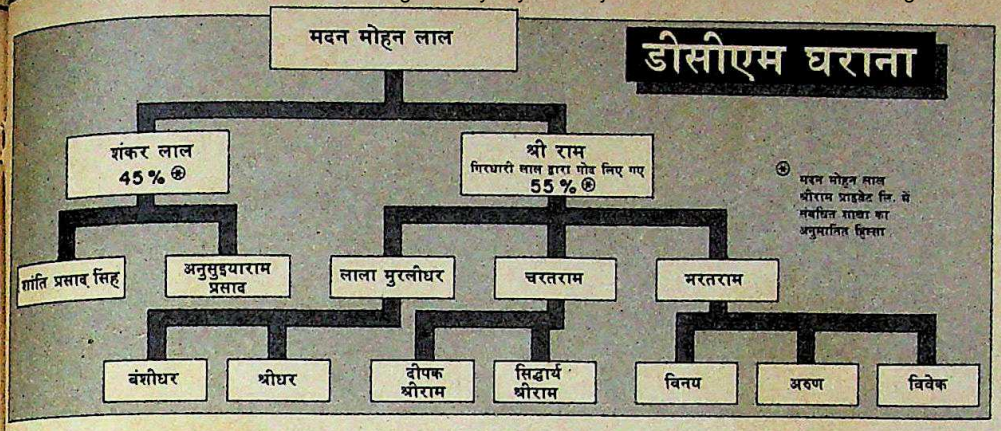

एसआरएफ और उसकी कुछ कंपनियों के माध्यम से इंग्लैंड स्थित व्यापारी स्वराज पाल से शेयर वापस खरीदे हैं और इस खरीद के लिए पैसा दिल्ली की अंसल प्रोपर्टीज ने उपलब्ध कराया.

अंसल प्रोपर्टीज के एक प्रवक्ता ने इस खबर का खंडन किया है. उसके मुताबिक अंसल वाले डीसीएम और दिल्ली की एक दूसरी कंपनी कैलाश नाथ ऐंड एसोसिएट्स के साथ मिलकर डीसीएम मिल की जमीन को विकसित करने में जरूर भागीदार हैं पर पैसा देने की बात बिलकुल गलत है.

लेकिन शेयर खरीदे जरूर गए हैं. इससे समूह की एक शाखा का दूसरों पर दबदबा बनने का अंदेशा पैदा हुआ ! दरअसल, स्वराज पाल और श्रीराम परिवार के बीच हुए एक समझौते में ये शेयर बहुत पहले खरीद लिए गए थे. यह बात दीगर है कि उनमें सभी का भुगतान नहीं किया गया था.

डीसीएम सूत्रों के मुताबिक श्रीराम फाइबर्स और उसकी कुछ कंपनियों ने स्वराज पाल के भाई जीत की कंपनियों से पांच फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी लेकिन यह तय था कि ये शेयर तीनों शाखाओं में बराबर-बराबर बांट दिए जाएंगे. उनके मुताबिक श्रीराम फाइबर्स ने ये शेयर अपने स्रोतों से ही खरीदे थे और शेयरों का ऐसे वक्त खरीदा जाना महज संयोग ही था. श्रीराम परिवार ने स्वराज पाल से शेयरों की कीमत चुकाने का वादा किया था. कुछ महीने पहले स्वराज पाल की कंपनियों ने उसे अपना वादा पूरा करने को लिखा था. इस पर श्रीराम परिवार ने 12 नवंबर तक हिसाब चुकता करने की बात कही थी. इसके बाद ही स्वराज पाल ने दबाव डालना शुरू किया.

स्वराज पाल ने ब्रिटेन से फोन पर इस बात की मोटे तौर पर तसदीक की. उन्होंने कबूल किया कि श्रीराम परिवार ने ढाई साल पहले डीसीएम में उनके 13 फीसदी शेयर खरीदे थे लेकिन पैसों का भुगतान न होने के कारण शेयरों को निलंबित खाते में डाल दिया गया. उन्होंने कहा, "मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते कुछ भुगतान हुआ है."

कलकत्ता में स्वराज के भाई जीत पाल ने बताया कि डीसीएम पर पाल बंधुओं का नौ करोड़ रु. बकाया था. इसमें से लगभग आधी रकम 1986 में चुका दी गई थी. बकाया रकम का अधिकांश भाग पिछले पखवाड़े दिल्ली में उनके दलाल हरीश भसीन के पास जमा कराया गया. डीसीएम को भसीन को उन कंपनियों की सूची भी देनी थी जिन्हें ये शेयर दिए जाने थे. लेकिन वह सूची उन्हें अभी तक नहीं मिली है. जीत ने यह भी बताया कि भुगतान स्टीलक्रेट लि. और सुरेंद्रा ओवरसीज लि. को किया गया. ये दोनों कंपनियां पाल बंधुओं की हैं.

इसके अलावा इस बंटवारे में और भी कई समस्याएं आड़े आ सकती हैं. उम्मीद है कि डीसीएम नियंत्री कंपनी रहेगी, जिसकी तीन सहयोगी कंपनियां होंगी. इस नियंत्री कंपनी को बाद में भंग कर दिया जाएगा. अब सवाल उठता है, तब कौन-सी कंपनी डीसीएम की करीब 79 करोड़ रु. की देनदारी संभालेगी? और अगर डीसीएम नियंत्री कंपनी बनती है तो क्या लाभ पर दोहरा कर नहीं देना होगा? इसके अलावा डीसीएम ने काफी पैसा नया सीमेंट कारखाना खोलने और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण में लगाया है. इससे उसे कुछ कर रियायतें मिल सकती हैं. लेकिन सहायक कंपनियां इसका दावा नहीं कर सकतीं.

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न कंपनियों में श्रीराम परिवार के बिखरे शेयरों को कैसे अलग किया जाए? तीनों शाखाओं के पास इतना पैसा नहीं कि वे एक दूसरे के शेयर खरीद सके.

इस परिवार के शेयर एक वित्त कंपनी—मदनमोहन लाल श्रीराम प्राइवेट लि. के पास हैं (इसके पास डीसीएम के आठ फीसदी शेयर हैं. श्रीराम फाइबर्स और बाकी फर्मों को भी इसमें शामिल किया जाए तो डीसीएम में परिवार की 20 फीसदी हिस्सेदारी है). माना जाता है कि श्रीराम परिवार के पास मदनमोहन लाल श्रीराम लि. की 55 फीसदी हिस्सेदारी है. लेकिन डीसीएम समूह के संस्थापक श्रीराम के भाई शंकरलाल के उत्तराधिकारियों के भी इस वित्त कंपनी में 45 फीसदी शेयर हैं जिससे डीसीएम में भी उनका दखल है. यदि बंटवारा होता है तो वित्त कंपनी में उनके शेयर भी खरीदने पड़ेंगे. पर उसके लिए पैसा कहां से आएगा?

इन मुद्दों पर अनेक सूत्र सहमत हैं लेकिन उनका कहना है कि प्रबंधक इन समस्याओं से निबटने की जिम्मेदारी किसी विशेषज्ञ फर्म को सौंपेंगे. समस्याएं ढेर हैं पर प्रबंधक इस बंटवारे को लेकर काफी उत्साहित हैं. शेयरधारकों की बैठक में बंसीधर को काफी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं.

—पलकुन्नथु जी. मथाई और ब्यूरो रिपोर्ट

भरतराम परिवार के पल्ले घाटे वाली इकाइयां आई हैं...

डीसीएम टेक्सटाइल मिल
डीसीएम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स
डीसीएम डाटा प्रोडक्ट्स
श्रीराम फाइबर्स
डीसीएम टोयोटा

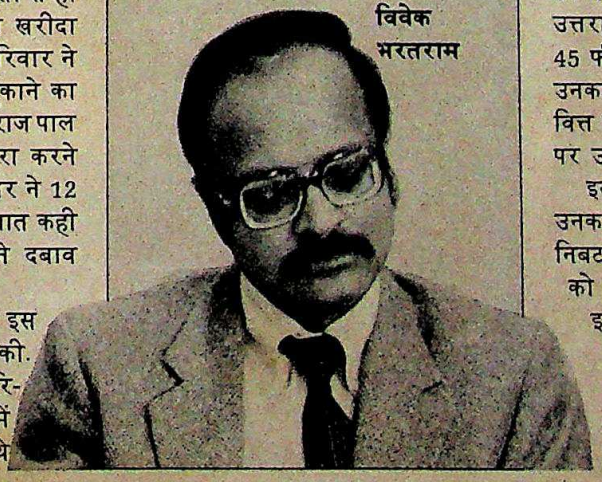

विवेक भरतराम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रेडिट कार्ड

उधार का उत्साह

सरकारी बैंक भी होड़ में शामिल

ऐसी होड़ पहले कभी नहीं रही. पहले एक ही क्रेडिट कार्ड मैदान में था. फिर तीन हो गए और अब तो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इनकी भरमार ला दी है. कुछ बैंक तो मास्टर कार्ड और वीसा जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्डों के साथ जुड़कर बाजार में आए पर दूसरे कई यह कारोबार चलाने के लिए सहयोगी कंपनियां खोल रहे हैं. और तो और, एक विदेशी बैंक भी कार्ड जारी करने वाला है, तो दूसरा इसके लिए बाजार की संभावनाएं तलाश रहा है.

इस होड़ का नतीजा यह है कि कुछ वर्ष पहले तक इस छोटे-से बाजार में जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक और निजी मालिकाने वाले डाइनर्स क्लब ऑफ इंडिया द्वारा जारी तीन कार्ड चलते थे, वहीं अब जल्दी ही 15 से ज्यादा कार्ड आने से गहमागहमी मच जाएगी. डाइनर्स क्लब के संयुक्त प्रबंध निदेशक पी. अग्रवाल कहते हैं, "हम होड़ बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं."

बैंकों की यह होड़ साल भर पहले उस समय तेज हुई जब भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कार्ड बाजार में लाए. उसके बाद कई छोटे राष्ट्रीयकृत बैंक अपने पांव जमाने के लिए पुराने महारथियों के साथ जुड़ गए. मसलन, वैश्य बैंक और युनाइटेड बैंक ने सेंट्रल बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी किए. तीन और बैंक उस रास्ते पर हैं.

बाजार में अभी गहमागहमी बढ़ेगी. स्टेट बैंक अपने छह सहयोगी बैंकों को कार्ड जारी करने की अनुमति देने की तैयारी में है. उधर, सरकार ने पहली दफा एक विदेशी बैंक को भी इस बाजार में उतरने की इजाजत दी है. ग्रिंडलेज़ बैंक अगले साल के शुरू में कार्ड जारी करेगा. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के लिए जाने माने अमेरिकन एक्सप्रेस ने यहां कारोबार की संभावनाओं का सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया है.

यही नहीं, सरकारी बैंक बाजार में अपनी स्थिति भी मजबूत कर रहे हैं. बैंक ऑफ इंडिया को कार्ड के कारोबार के लिए एक सहयोगी कंपनी स्थापित करने की सरकारी अनुमति मिल गई है. चार दूसरे बैंक इसमें पूंजी लगाएंगे. सेंट्रल बैंक भी इसके लिए एक सहयोगी कंपनी खोल सकता है. केनरा बैंक में कार्ड विभाग के महाप्रबंधक दिनेश नायक कहते हैं, "पहले साल में ही हम अपने लक्ष्यों से आगे निकल गए हैं. बाजार का रुख उत्साहवर्द्धक है."

बाजार कितना उत्साहवर्द्धक है या इस मामले में बाजार कितना बड़ा है, इस उद्योग में यह तय कर पाना मुश्किल है. इसकी सारी तफसीलें बहुत गोपनीय रखी जाती हैं. फिर भी, सूत्रों का अनुमान है कि 70,000 सदस्यों वाले डाइनर्स क्लब ने पिछले साल 75 करोड़ रु. का कारोबार किया. इसके बाद सेंट्रल बैंक (सदस्य संख्या 40,0000) का स्थान है जिसका कारोबार करीब 50 करोड़ रु. रहा. तीसरे स्थान पर करीब 42 करोड़ रु. के कारोबार वाला आंध्र बैंक (सदस्य संख्या 40,000) है.

इन आंकड़ों से लगता है कि यह कारोबार 160 करोड़ से अधिक का ही है. क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाले बंबई के ओबेराय टॉवर्स के परिचालन प्रबंधक संजीव मलहोत्रा बताते हैं, "क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हमारी 80 फीसदी आमदनी होटल में ठहरने वाले विदेशियों से होती है. देशी लोग इसका कम ही इस्तेमाल करते हैं." अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को छोड़कर भारतीय क्रेडिट कार्ड का बाजार 60 करोड़ रु. से अधिक नहीं बैठता है. देश में क्रेडिट कार्ड-धारकों की संख्या महज 1.5 लाख आंकी गई है. यहां के करीब 60 लाख करदाताओं के मुकाबले यह संख्या बहुत कम है.

और यही विडंबना भी है. हर कोई छोटे-से बाजार में उतरने को उतावला है. पर कामयाबी कुछ के ही हाथ लगी है. 15 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच बाजार पर कब्जा करने की होड़ की वजह से क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाले प्रतिष्ठानों की चांदी हो गई है. उन्होंने बैंकों के कमीशन में भी कटौती कर दी है. बंबई के एक प्रमुख डिपार्टमेंट स्टोर के प्रबंधक का कहना है, "पहले अमूमन चार से छह फीसदी कमीशन दिया जाता था. आज यदि कोई बैंक किसी तरह तीन फीसदी पाने में भी कामयाब हो जाए तो खुद को भाग्यशाली मानता है."

लेकिन बिना मुनाफे वाले इस धंधे में कूदने की मारामारी की वजह आखिर क्या है. ज्यादातर बैंक अपने पारंपरिक धंधे में थोड़ी तब्दीली करने को उत्सुक हैं. सिटी बैंक ग्राहक सेवा समूह के उपाध्यक्ष सुरेन खिरडवाडकर का कहना है, "क्रेडिट कार्ड और स्वचालित टे'लर मशीन भारतीय बैंक उद्योग में नई-नई व्यवस्था ही है. इसकी दीर्घकालीन संभावनाएं अच्छी हैं." बंबई में बैंक ऑफ अमेरिका के उपाध्यक्ष तुषार चोपड़ा निजी बैंकिंग के संबंध में कहते हैं, "बढ़ता मध्यम वर्ग और उपभोक्ता सामान का फलता-फूलता बाजार इस बात के संकेत हैं कि क्रेडिट कार्ड की संभावनाएं बेहद अच्छी हैं."

राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी सद्बुद्धि आ गई लगती है. उन्होंने वित्त मंत्रालय को अनेक सुझाव दिए हैं. एक तो यह कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्रेडिट कार्डों, ट्रेवलर व गिफ्ट चेकों और स्वचालित टे'लर मशीनों के कामकाज को मिलाकर एक कर दिया जाए. इससे बड़ी शेयर पूंजी वाली नई कंपनी बाजार में आसानी से पांव जमा सकेगी. धंधे के विलय से क्रेडिट कार्ड के बाजारों में सचमुच उनकी तूती बोलने लगेगी.

—एस.एन. वासुकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मूंगफली

तेल की धार

कीमतें गिरीं, किसान परेशान

भरपूर फसल से आई खुशहाली से क्या मुश्किलें होती हैं यह भारत के सबसे प्रमुख मूंगफली उत्पादक क्षेत्र, सौराष्ट्र में देखने को मिल रहा है. लगातार कई वर्षों के सूखे के बाद इस बार जब भरपूर फसल हुई तब भी वहां के किसानों के चेहरों पर रौनक नहीं लौटी है. सभी प्रमुख खरीदी केंद्रों के गोदाम भर जाने से कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है.

जुलाई तक 15 किलो तेल का टिन 400 रुपए से अधिक में बिक रहा था, जो अब 260 रुपए पर आ गया है. पिछले साल 20 किलो मूंगफली 200 रु. तक में बिकती थी जो अब मात्र 110 रु. में मिलने लगी है.

ऐसी स्थिति में अब स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देकर किसानों से कहा जा रहा है कि वे अपना माल थोक मंडी में न लाएं. सौराष्ट्र के चार बड़े केंद्रों—राजकोट, जूनागढ़, धोराजी और उपलेटा के गोदाम भर जाने से ऐसा करना जरूरी हो गया है.

करीब 1000 करोड़ रु. की मूंगफली अभी भी बिकने के लिए पड़ी है. इस कारण स्थिति और खराब हो गई है. किसान मूलजी पटेल कहते हैं, "स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है. खुले में जो सैकड़ों करोड़ की फसल पड़ी है वह बारिश की एक बौछार से बर्बाद हो सकती है." गुजरात कोऑपरेटिव ग्रोवर्स फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) अगर सारी ताकत लगाकर भी खरीद करे तो वे 200 करोड़ रु. से अधिक की मूंगफली नहीं उठा पाएंगे. जूनागढ़ के मझोले स्तर के किसान वाघजी पटेल कहते हैं, "हम तो बर्बाद हो गए हैं. सरकार को कुछ करना चाहिए."

गुजरात सरकार भी चिंतित है पर वह बहुत कुछ नहीं कर रही है. उसने सिर्फ केंद्र और नेफेड से अधिक से अधिक खरीद करने का आग्रह किया है. कीमत कम होते जाने से किसान यह फसल पैदा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे. इसका दूरगामी असर देश के भुगतान संतुलन पर पड़ेगा.

खाद्य तेलों का उत्पादन पूरा न होने से पिछले साल 1061 करोड़ रु. का खाद्य तेल विदेशों से मंगाना पड़ा. सरकार आयात के खर्च को कम करने और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तेल की कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि करती जा रही है.

इस साल गुजरात ने करीब 20 लाख टन मूंगफली के दाने पैदा किए हैं. यह 18 वर्षों में सबसे अधिक है. पिछले साल मात्र एक लाख टन और उससे पिछले साल 13 लाख टन मूंगफली का उत्पादन हुआ था.

राजकोट भेजी जा रही मूंगफली

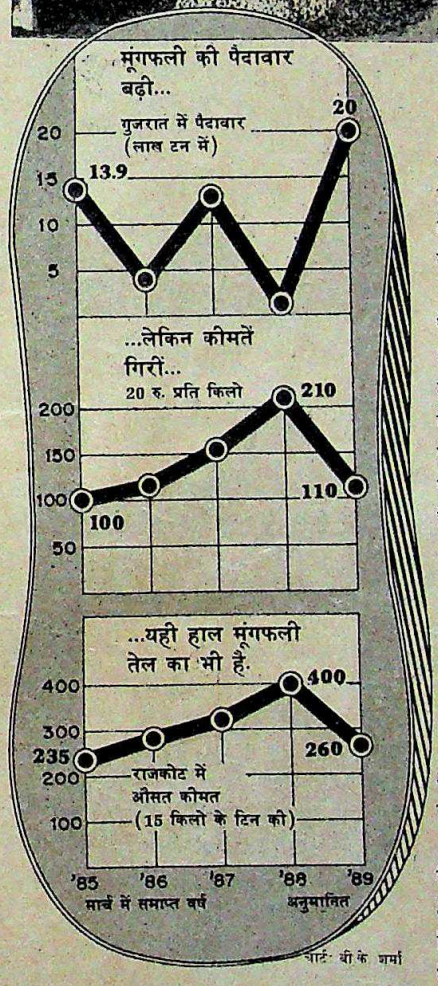

लेकिन इस सबका 'खामियाजा' भी किसानों को ही भुगतना पड़ेगा. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष वी.कुरियन ने कहा, "जब कभी किसान अच्छी पैदावार करता है, उसके पेट पर मार पड़ती है."

कीमतों में गिरावट से अजीब स्थिति पैदा हो गई है. आज मूंगफली का तेल अधिकांश खाद्य तेलों से सस्ता है, कपास के बीज, सरसों, तिल और सूर्यमुखी के तेल से भी सस्ता. इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस साल सोयाबीन की फसल अच्छी हुई है. इसलिए मूंगफली के तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है. सॉल्वेंट एक्स्ट्रेक्टर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और खाद्य तेल उद्योग के अनेक वर्षों तक प्रवक्ता रहे चंदूभाई कोठारी कहते हैं, "दरअसल यह गिरावट सिर्फ अटकलबाजी के कारण है. इस साल तो नया तेल बाजार में पहुंचने के पहले ही तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है." वे चेतावनी देते हैं कि अगर कीमतों में और गिरावट आई तो तेल उद्योग के लिए बहुत बुरा होगा.

यह स्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी. किसानों, तेल मिल मालिकों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों तक की राय है कि सरकारी सुस्ती और दीर्घकालिक योजना के अभाव के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है. धोराजी के एक मिल मालिक मगनभाई पटेल कहते हैं, "जब मूंगफली की बुआई शुरू हो गई थी, तब भी सरकार तेल का आयात करती रही. ऐसा स्पष्ट नीति के अभाव के कारण हुआ. जरूरत तो इस बात की है कि बुआई के मौसम से पहले ही विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर स्पष्ट नीति बना ली.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुजरात कोऑपरेटिव ग्रोवर्स फेडरेशन और राज्य कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार उन लोगों ने मूंगफली बाजार में स्थिरता लाने के लिए केंद्र को अपने सुझाव भेजे थे. इनमें बड़ा भंडार जमा करना, आयात कम करना, मंदी-काल को छोड़कर आयातित तेल कम मात्रा में बाजार में भेजना और पर्याप्त तिलहन पैदा करने वाले राज्यों को कम तेल देने के सुझाव शामिल थे.

लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. कोठारी कहते हैं, "यह एकदम साफ है कि सरकारी काम टालू ढंग से चलता है. सरकारी नीतियों में एकरूपता आने से ही कीमतें स्थिर होंगी." गुजरात कृषि विश्व-विद्यालय के एक निदेशक बी.जे. जाडेजा कहते हैं, "सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाला मूल्य-स्तर बनाए रखने के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों, बैंकों और सरकारी एजेंसियों को मिलजुलकर काम करना चाहिए."

गुजरात कोऑपरेटिव के एक अधिकारी ने सुझाव दिया था कि स्थिति सुधारने के लिए सरकार मूंगफली का समर्थन मूल्य 430 रु. क्विंटल से बढ़ाकर 600 रु. क्विंटल कर दे. 430 रु. में तो किसानों का लागत मूल्य भी मुश्किल से निकलता है. उनका सुझाव है कि अगर सरकार की मंशा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर तेल देने की है तो उसे फसल के मौसम में खरीद करने, खरीदा हुआ माल भंडार में रख लेने और मूल्य वृद्धि के समय तेल निकालने की स्पष्ट नीति बनानी चाहिए.

लेकिन केंद्र ने अपनी तिलहन नीति में बदलाव किया है. उसने 600 रु. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की बात तो नहीं मानी पर इसे 430 रु. बढ़ाने का संकेत जरूर दिया है. केंद्र ने भंडार करने और उसका जिम्मा मौजूदा एजेंसी को देने की भी बात मान ली है. तिलहन योजना के निदेशक शेनॉय भी कहते हैं कि सरकार तिलहन खरीदने के लिए वचनबद्ध है. वे कहते हैं, "पहली किस्त के तौर पर नाफेड को सभी फसलों के लिए 120 करोड़ रु. दिए गए हैं. पैसा कोई समस्या नहीं है." फिर भी यह सब होते तक किसानों के सिर पर से पानी गुजर चुका होगा.

इस मामले में फ़ायदे की बात यह है कि इससे इस साल तेल के आयात का खर्च आधा ही रह जाएगा. तकनीकी आयोग ने सुझाव दिया है कि पिछले वर्ष (अक्तूबर में समाप्त वर्ष) के 18.5 लाख टन की तुलना में इस साल आठ लाख टन तेल ही मंगाया जाए. अभी कुछ दिनों तक गृहिणियों को भी तेल सस्ता मिलेगा. अगर तेल रिफाइंड करने वाली कंपनियों की बात पर भरोसा करें तो इस तेल की खुदरा कीमत भी कम रहेगी.

आम धारणा यह है कि अगर सरकारी मशीनरी ठीकठाक चलने लगे और अधिक तेल मिलें कामकाज शुरू करें तो आने वाले महीनों में मूंगफली का तेल 15 किलो वाले टिन में 280 रु. से 320 रु. तक में बिकेगा जो कुछ समय पहले तक 400 रु. में मिलता था. गुजरात की 1000 तेल मिलों में से 20 फीसदी और 58 साल्वेंट मिलों में से आधी सूखे के कारण बंद पड़ी हैं.

पर असहाय किसानों को आंकड़ेबाजी में बहुत भरोसा नहीं है. वे सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण नाराज हैं. तमाम मुश्किलें उठाकर उन्होंने जो फसल पाई है, उसकी वे वाजिब कीमत चाहते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले आम चुनाव के समय वे अपनी नाराजगी वोट के रूप में प्रकट कर सकते हैं.

—उदय माहूरकर, ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

एस. एस. शेट्टी

अनोखी भूमिका

प्रबंधक से बने मजदूर नेता

चेन्नागिरी सुब्बाशेट्टी सत्यनारायण शेट्टी (65) एन्नोर फाउंड्री कर्मचारी संघ के नए अध्यक्ष हैं. लेकिन इसमें नया क्या है? उनका पिछला जीवन: शेट्टी आठ वर्षों तक कंपनी के प्रबंध निदेशक थे.

1700 सदस्यों वाले संघ के चुनाव में उन्होंने बुजुर्ग मजदूर नेता आर. कुचेलर को 1000 से अधिक मतों से हराया. इस नतीजे के बारे में 40 करोड़ रु. कारोबार वाली इस कंपनी के मौजूदा प्रबंध निदेशक डी. वासुदेव राव कहते हैं, "अब कुछ पेशेवर रुख की उम्मीद की जा सकती है. अगर वे सहयोग का रुख अपनाते हैं तो इससे कंपनी का भला होगा."

शेट्टी भी मजदूर आंदोलन में प्रबंधकीय तकनीकों को शामिल करने की बात करते हैं. ये तकनीकें क्या होंगी, यह उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है पर उन्होंने "फैक्टरी की अराजक स्थिति" को ठीक करने के लिए दो साल की अवधि जरूर तय की है. हां, मजदूर नेता की उनकी नई भूमिका प्रबंधकों के लिए निश्चित रूप से सिरदर्द साबित होगी. शेट्टी कहते भी हैं, "उनमें से हरेक मेरे अधीन काम कर चुका है और मैं उनसे काम लेना जानता हूं." मजदूर संघ के उपाध्यक्ष एस. पीटर्स कहते हैं, "प्रबंध निदेशक के रूप में उनका अनुभव हमारे लिए सबसे लाभप्रद रहेगा."

खिचड़ी बालों वाले इस पूर्व प्रबंध निदेशक ने प्रबंधकों को तुरंत एक मांगपत्र पकड़ा दिया. इसमें दो मांगें हैं: अवकाश पाने वाले हर कर्मचारी के एक आश्रित को नौकरी और मजदूरों की शिकायत प्रबंधकों तक पहुंचाने के लिए मजदूर संघ के प्रत्येक अधिकारी को पूरी आजादी. फिर भी उन्हें यह गलतफहमी नहीं है कि उनका काम एकदम आसान होगा. शेट्टी कहते हैं, "हमें प्रबंधकों की ओर से कड़े प्रतिरोध का सामना करना होगा."

शेट्टी मद्रास के बाहरी इलाके में स्थित इस कंपनी में 1971 से 1979 तक प्रबंध निदेशक थे. धातु विज्ञान में उपाधिधारी और ढलाई के काम के विशेषज्ञ शेट्टी ने अपने कार्यकाल में केबिन में बैठने के बजाय कारखाने की मशीनों पर ज्यादा समय गुजारा इस कारण मजदूरों से उनका गहरा रिश्ता बना. उन्होंने कंपनी में ब्रिटेन की लेलैंड कंपनी के शेयर 92 फीसदी से कम कराए और प्रबंध के ऊंचे पदों पर अधिक संख्या में भारतीयों की नियुक्ति की. बाद में प्रबंधक मंडल के विवाद के कारण

शेट्टी (बाएं) का स्वागत: नई भूमिका

उन्हें पद छोड़ना पड़ा.

बाद के नौ वर्षों तक उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रबंधकीय सलाह देने का काम किया. यदि किस्मत ने पलटा न खाया होता तो वे प्रबंधकीय सलाह देने का काम कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

माइको स्पार्क. लाखों की पसंद, हर वाहन के संग.

प्रतिदिन लाखों वाहनों को गति देता है माइको.

स्पार्क प्लग तकनीक में विश्व ख्याति प्राप्त पश्चिम जर्मनी बॉश के सहयोग से बना — 'माइको सुपर' — अत्यधिक आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण — भारत का प्रथम बाइमेटल स्पार्क प्लग.

इसीलिए, आप जानी मानी बेहतरीन क्वालिटी का माइको स्पार्क प्लग ही हर बार लगाएं और निश्चिंत वाहन चलाएं.

MICO

LICENCE BOSCH

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कई उत्पादों वाली एक बहु-आयामी कंपनी जिसे भारत में ऊंचे दर्जे की टैक्नोलॉजी लाने का श्रेय है

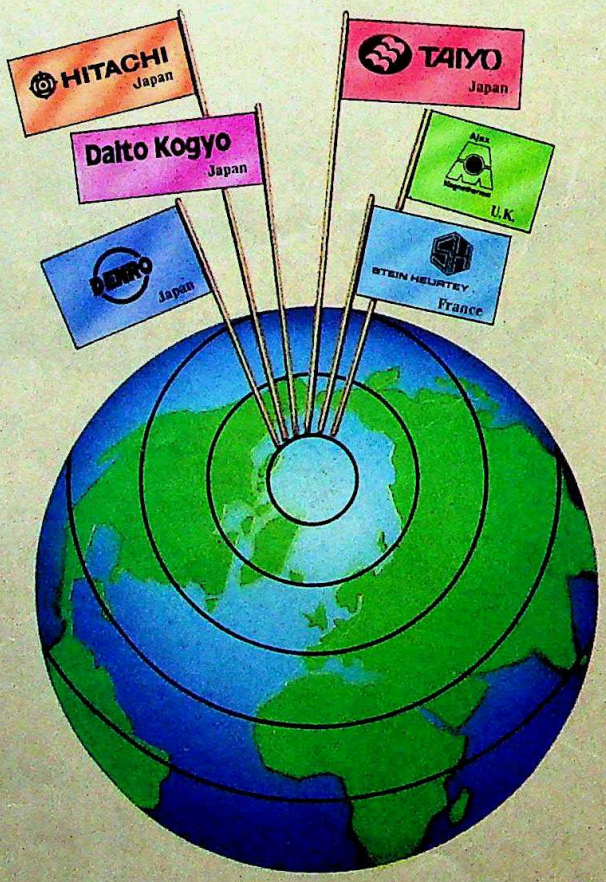

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निप्पॉन डेनरो इस्पात—एक ऐसी कंपनी जो भारत में सबसे ऊंचे दर्जे की टैक्नोलॉजी लाने के प्रति समर्पित है. आयात के शत-प्रतिशत वैकल्पिक उत्पाद तैयार करने के अभियान की अगुआई करते हुए यह कंपनी विदेशी मुद्रा बचाने में व्यापक सहयोग दे रही है.

निप्पॉन डेनरो इस्पात की इस अगुआई की कहानी 1985 में शुरू हुई जब **निप्पॉन डेनरो मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., जापान** के साथ तकनीकी सहयोग से भारत में कम मोटाई वाली गैल्वेनाइज़्ड इस्पात चादरें तैयार करने वाले संयंत्र ने काम करना शुरू किया.

निप्पॉन डेनरो इस्पात ने अब जापान के विख्यात और बड़े औद्योगिक संगठन **हिताची लि. आफ जापान** के साथ मिलकर एक अति आधुनिक 6 हाई-कम्बिनेशन रिवर्सिबल कोल्ड रोलिंग मिल लगाई है जो निर्धारित समय से पहले ही अक्तूबर 1988 में उत्पादन आरंभ कर चुकी है. इसके उत्पादनों में तरह-तरह की कोल्ड रोल की हुई चादरें हैं. जिनमें ऐसी अत्याधिक पतली चादरें भी हैं जो पहली बार भारत में तैयार की जा रही हैं. इस संयंत्र को चलाने और रख-रखाव की जानकारी **ताल्यो स्टील आफ जापान** द्वारा उपलब्ध कराई गई है. कोल्ड रोलिंग मिल इकाई में कांटिनुअस पिकलिंग लाइन तथा इलेक्ट्रोलिटिक क्लीनिंग को नियंत्रित करने वाली आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निप्पॉन डेनरो आफ जापान ने अपनी टैक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है.

इसके अलावा निप्पॉन डेनरो आफ जापान तथा **डेल्टो कोग्या आफ जापान** के साथ सहयोग से एक और संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो भारत में पहली बार पीवीसी या रंग की परत वाली इस्पात की चादरें तैयार करेगा. आशा है कि यह संयंत्र 1989 की पहली तिमाही में काम करना शुरू कर देगा.

इसके साथ ही **स्टाइन-ह्यूर्टी आफ फ्रांस** तथा **एजेक्स मैग्नेथर्मल आफ यू.के.** के सहयोग से मौजूदा गैल्वेनाइज़िंग इकाई का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है. इससे गैल्वेनाइज़िंग संयंत्र में प्रति टन निवेश लागत में कमी आएगी और इस तरह उत्पादन खर्च में कटौती होगी. इसके अलावा विभिन्न कामों में इस्तेमाल हो सकने वाली नई किस्म की परतदार इस्पाती चादरों की एक नई श्रेणी का उत्पादन भी किया जाएगा.

और इस तरह निप्पॉन डेनरो इस्पात दुनिया भर में उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीकों का एक ऐसा सफल मिश्रण है जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर खरे उतरने वाले उत्पाद भारत में तैयार कर रही है.

ISPAT

निप्पॉन डेनरो इस्पात लिमिटेड

पार्क प्लाज़ा, 71 पार्क स्ट्रीट. कलकत्ता 700 016

हमीं हैं अव्वल. हमीं से है भविष्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

PRESSMAN

WALL-TO-WALL UNCARPETING FROM JOHNSON

Ignore the exceptional strength of Johnson's designer floor tiles.

And the fact that they're just one-third the weight of mosaic.

Remain unimpressed by their exceptional scratch-resistance.

And turn a deaf ear to their unique anti-echo property.

They also happen to be fire-proof, stain-proof, acid-resistant and dust repellant. But don't let that sway you.

Allow yourself, instead, to fall hopelessly in love with their looks.

They're available in three sizes: 8x4, 8x8, or 12x12.

And fifteen tasteful colours: silver grey, leather, off-white, apple brown, coffee, green, ivory, amber, dholpur pink, almond, mushroom, tan, ebony brown, pale grey and speckle.

A glamorous alternative to mosaic, granite, marble or stone.

For homes and offices. Hotels and auditoriums.

Whether you follow your head or your heart, you'll agree:

They're the best thing that's happened to floors since the wall-to-wall carpet.

JOHNSON
DESIGNER FLOOR TILES

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहे होते. 23 वर्षों में पहली बार, पिछले वर्ष, मजदूर संघ के पदाधिकारियों का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ. इसमें कारखाने के एक श्रमिक एन. त्यागराजन जीत गए. फिर जब इस साल चुनाव का समय आया तो त्यागराजन ने अपनी जगह लेने के लिए योग्य आदमी की तलाश शुरू की. और उन्हें अपने पूर्व प्रबंध निदेशक से ज्यादा योग्य कोई नहीं दिखा.

त्यागराजन बताते हैं, "मजदूरों और प्रबंधकों का रिश्ता इस बुरी स्थिति में पहुंच गया था कि हमें यह कदम उठाना ही पड़ा." (वैसे प्रबंध निदेशक राव कहते हैं कि प्रबंध के मजदूरों से रिश्ते अच्छे हैं) मजदूर प्रबंध निदेशक के रूप में शेट्टी के कार्यकाल को स्वर्णिम मानते हैं. मजदूरों को उन पर पूरा भरोसा था इसीलिए त्यागराजन शेट्टी के पास पहुंचे. शेट्टी कहते हैं, "मैंने इस मामले पर दो दिनों तक विचार किया और फिर हां कर दी क्योंकि मजदूर मुझ पर इतना भरोसा व्यक्त कर रहे थे."

शेट्टी ऐसे समय में कंपनी के कामकाज में फिर से शामिल हुए हैं जब मजदूरों से बेहतर संबंध बनाने की तीव्र आवश्यकता है. एन्नोर फाउंड्रीज ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड के लिए ढलाई का काम है. आठ महीने पहले इसे हिंदुजा और फिएट की सहयोगी इवेको ने खरीद लिया. अब उन्होंने इस कंपनी के लिए भारी-भरकम योजनाएं बनाई हैं. इनमें 20 वर्ष पुराने कारखाने को दस करोड़ की लागत से बदलने की योजना भी है. 1961 में निर्माण के बाद से यह कंपनी पहली बार निर्यात बाजार में उतरने जा रही है. पुराने प्रबंध निदेशक की अनोखी भूमिका में वापसी के साथ ही इन योजनाओं पर बारीकी से विचार करना होगा. —ललिता दिलीप

कोका कोला

घुसने की तैयारी

कानूनी छूटों के सहारे

विश्व की सबसे बड़ी व्यावसायिक लड़ाई भारत में भी छिड़ने जा रही है. पेप्सी कोला के भारत आने की अर्जी पर मंजूरी की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि उसकी चिर प्रतिद्वंदी कोका कोला ने भी पिछले पखवाड़े भारत में प्रवेश की अर्जी दे दी. स्पष्ट है कि इन दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर 600 करोड़ रु. के भारतीय शीतल पेय बाजार पर है.

स्वाभाविक है कि इससे स्थानीय कंपनियां खुश नहीं हैं. पारले के प्रमुख रमेश चौहान कहते हैं, "दुनिया में सिर्फ अपने देश में ही विदेशी शीतल पेयों का प्रवेश नहीं है. और अब पूर्ण आत्मनिर्भरता से हम बहुराष्ट्रीय निगमों की गुलामी में ढकेले जा रहे हैं, वह भी उस साल जब देश आत्मनिर्भरता के पिता (नेहरू) की जन्मशती मना रहा है."

पेप्सी को बगल के दरवाजे से प्रवेश मिला है. वह वोल्टास और पंजाब-एग्रो के साथ 40 फीसदी भागीदारी करके फल-सब्जियों और अनाज के प्रसंस्करण, कृषि विषयक शोध तथा शीतल पेय के काम में उतर रही है. लेकिन कोका कोला ने भारतीय बाजार के पिछले दरवाजे में कुछ सुराख ढूंढ़ लिए हैं. उसका दिल्ली के निकट नोएडा निर्यात क्षेत्र में कंसंट्रेट बनाने की इकाई लगाने का प्रस्ताव है. कुछ ही दिन पहले घोषणा की गई थी कि पूर्णतः विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां भी ऐसे क्षेत्र में अपनी इकाई लगा सकती हैं. मुख्यतः भारतीय निर्यातकों के लिए ऐसे क्षेत्र बनाने की योजना बहुत सफल नहीं रही है. इसलिए सरकार ने इन नियमों में ढील दी. ऐसे क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के आने की छूट भी इसी का नतीजा है. मार्च में इसके लिए एक छूट और दी गई कि इन क्षेत्रों में तैयार माल का 25 फीसदी माल देसी बाजार में भी बेचा जा सकता है.

कोका कोला के अधिकारी इसमें कोई संदेह नहीं रहने देना चाहते कि उन्होंने इन्हीं कानूनी छूटों के आधार पर देश में पांव जमाने की सोची है. कोका कोला के विपणन विकास निदेशक (अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया) स्टुअर्ट ईस्टवुड बताते हैं कि यहां निर्यात दुनिया भर के कोका कोला नेटवर्क का हीं हिस्सा होगा.

मुक्त निर्यात क्षेत्र के नियमों के अनुसार वहां पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाली इकाई लग सकती है और इसका सारा मुनाफा विदेशी कंपनी ले जा सकती है. यह नियम कोका कोला को भी रास आ रहा है जो अपने कंसंट्रेट का गुप्त 7 एक्स फार्मूला सिर्फ उसी इकाई में तैयार करती है जो उसके पूर्ण स्वामित्व में रहती है. 1977 में इसने भारत से निकलना ही बेहतर समझा था क्योंकि उसे किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर कंसंट्रेट बनाने को कहा गया था. उसने 27 साल से जमा-जमाया अपना कारोबार उठा लिया लेकिन यह फार्मूला दूसरे हाथों में जाने नहीं दिया.

कोका कोला इस प्लांट पर 20 लाख डॉलर (तीन करोड़ रु.) लगाना चाहती है. आधा कच्चा माल यहीं से खरीदा जाएगा और यहां इसकी कीमत का 86 फीसदी जोड़ा जाएगा. इसके लिए विशेष रियायत की जरूरत नहीं होगी. फिर भी यह फैसला राजनैतिक होगा क्योंकि प्रस्ताव घरेलू बाजार में घुसने के लिए निर्यात

पेप्सी को पिछले दरवाजे से प्रवेश मिला है. लेकिन कोका कोला नोएडा में कोला कंसंट्रेट बनाने की इकाई का प्रस्ताव लेकर आई है

संवर्द्धन वाली रियायतों का फायदा उठाने का है. एक अधिकारी का कहना है, "इससे दूसरी विदेशी कंपनियों के लिए घुसपैठ का रास्ता खुल जाएगा. कल आईबीएम आ जाए तो क्या होगा?"

दूसरे सवाल भी हैं. ऐसी इकाइयों से जो माल घरेलू बाजार में आता है उस पर सीमा शुल्क लगाया जाता है. लेकिन वस्तुओं की सूची में शीतल पेय के कंसंट्रेट का नाम ही नहीं हैं. इसलिए हो सकता है इस माल पर कोई शुल्क भी न मिले.

पिछले कई वर्षों से कोका कोला से गठबंधन के लिए कई कंपनियां, जिनमें मैकडोवेल भी है, उसके पास पहुंच चुकी हैं. अभी तो इस मामले में सबसे आगे गोदरेज है. गोदरेज सोप्स के प्रबंध निदेशक ए.बी. गोदरेज कहते हैं कि "अगर गोदरेज के साथ यह गठबंधन हुआ तो इसे नोबल सोया के साथ जोड़ दिया जाएगा."

कोका कोला का भागीदार कोई भी बने पर यह एकदम साफ दिख रहा है कि वह भारतीय बाजार में घुसने वाली है. चौहान कहते हैं, "पेप्सी आ गया तो आज नहीं तो कल कोका को आना ही था."

—डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

खुशहाली कायम

पिछड़ों के भी दिन फिरे

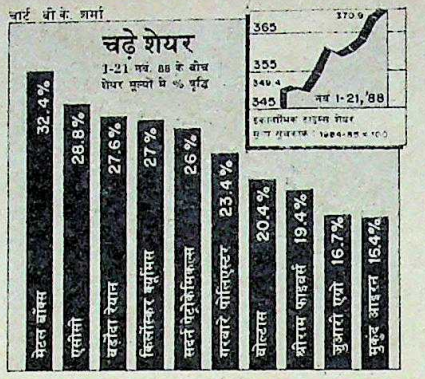

शेयर बाजार बुलंदियों पर है, शेयरों की कीमतें ऊपर ही चढ़ती जा रही हैं, नए रिकार्ड बना रही हैं और हर शेयर अपनी औकात से कहीं ज्यादा बढ़-चढ़कर बोल रहा है. और बाजार में नए शेयर के लिए भी काफी संभावनाएं हैं.

हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि रामा फाइबर्स, बिहार कॉस्टिक, पेप्को इंडस्ट्रीज और सम्राट बाइसाइकिल जैसे शेयर जो अरसे से पिछड़े हुए थे, उनमें भी 100 से 300 फीसदी तक उछाल आ गया है. और मौसम के जरिये देश पर खुदा की इनायत थी, सो उर्वरक कंपनियों के भी वारे-न्यारे हुए. इसके अलावा जिन कंपनियों के शेयरों ने खासा पैसा कमाया उनमें सीमेंट और दवा कंपनियां प्रमुख थीं. मसलन, एसोसिएटेड सीमेंट के शेयरों में 59 फीसदी उछाल आया और हिंदुस्तान सीबा गाइगी के शेयरों में 20 फीसदी. बाजार की अगुआई करने वाले शेयर भी तेजी से चढ़े.

बाजार की यह रवानी बंबई शेयर बाजार के सूचकांक में भी दिखी. 30 शेयरों की कीमतों पर आधारित यह सूचकांक 9 नवंबर से 19 नवंबर के बीच 709.03 से चढ़कर 719.07 पर पहुंच गया. बाकी शेयरों में भी खासी तेजी के लक्षण थे. 9 से 21 नवंबर के बीच इकॉनॉमिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक 360.7 से उछलकर सीधे 370.9 पर जा पहुंचा.

खुशहाली के इस माहौल में बंबई शेयर बाजार में एक समस्या भी आड़े आई. इसका कुल धंधा इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि संभाल पाना मुश्किल हो गया है. 22 नवंबर को बाजार बंद कर दिया गया ताकि जिन "शेयरों का नकद धंधा हुआ है उनका निबटारा" हो सके. और जब पिछले दो महीने से रुके पड़े कामों का निबटारा करने के लिए देश का यह सबसे प्रमुख शेयर बाजार बंद करना पड़ा तो जाहिर है कि बाजार में आए उछाल ने बाजार की कुछ अहम कमजोरियों को उजागर कर दिया.

ये कमजोरियां आगे भी बाजार के अधिकारियों को परेशान रखेंगी, जबकि वे शेयरों की खरीद-फरोख्त पर 20 फीसदी पड़ता वसूल रहे हैं. कलकत्ता में भी दलालों को एक लाख रुपए तक के कड़े जुर्माने झेलने पड़े हैं. लगता है बाजार कुछ ज्यादा ही गरम हो गया है.

इन कार्रवाइयों का एक नतीजा यह हुआ कि वायदा बिक्री में पैसा लगाने वालों ने ब्याज की दरें बढ़ा दीं. पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों की कार्रवाई का बाजार पर कोई असर होगा भी. पिछले पखवाड़े के आखिर तक तो इसके संकेत नहीं थे. फिलहाल तो माहौल पर तेजी ही हावी है. पर आने वाला समय स्थिति को और ज्यादा साफ कर देगा.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	बंद 21.11.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	70.50	30.25	70.50	7.75 +
एसोसिएटेड सीमेंट	399.00	128.50	391.00	59.00 +
एटलस कॉप्को	66.00	33.50	55.00	2.00 --
एशियन पेंट्स	232.50	128.75	227.50	12.50 +
बजाज ऑटो	520.00	187.50	410.50	27.50 +
बड़ौदा रेयॉन	385.00	140.00	370.00	65.00 +
बाटा इंडिया	89.00	50.50	87.00	4.00 +
भारत फोर्ज	200.00	101.00	195.50	10.00 +
बिरला जूट	55.00	32.25	53.50	7.00 +
ब्ली प्लास्ट	125.00	28.00	47.00	5.50 --
बांम्बे डाइंग	159.50	94.00	138.50	5.50 +
बुक बाड	122.00	75.00	116.00	6.00 +
ब्रिटानिया इंडिया	121.00	75.00	112.00	3.00 +
सेंचुरी स्पिनिंग	1535.00	617.50	1480.00	30.00 +
क्लोराइड इंडिया	83.00	59.00	80.00	4.00 +
कोलगेट	335.00	160.00	320.00	7.50 +
सायनामिड	72.50	33.00	64.00	1.50 +
डीसीएम	55.00	28.00	35.75	7.50 --
इनलप	97.00	66.00	97.00	12.00 +
ईआई होटल्स	62.50	38.00	60.00	4.00 +
एस्कार्ट्स	72.00	37.00	68.00	3.50 +
फिलेक्स केबल्स	435.00	237.50	380.00	10.00
फूड स्पेशिलिटीज	178.75	93.50	175.00	5.00 +
गरवारे नाइलॉन	58.00	20.00	47.00	—
जी.ई. शिपिंग	45.00	20.50	43.00	—
गुजरात स्टेट फर्टि.	172.00	75.00	147.50	8.75 +
ग्रासिम इंडिया	118.00	74.00	91.00	10.00 +
हिंदु. सीबा	691.00	332.50	660.00	20.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	126.25	15.00 +
हिंदुस्तान लीवर	92.00	59.50	84.00	1.00 +
हिंदुस्तान मोटर्स	34.00	15.80	30.60	0.70
हिंदु. एल्यूमिनियम	141.00	73.00	137.00	12.00 +
आई.ई.एल.	59.50	31.00	54.00	1.00
इंडियन ऑर्गेनिक	51.00	15.00	48.00	5.00 +
इंडियन रेयन	90.00	46.00	88.00	7.50 +
इड्राल	291.25	133.75	265.00	5.00 —
इगरमॉल-रैड	370.00	205.00	325.00	5.00 +
आई.टी.सी.	64.00	30.00	48.50	2.25 --
जे.के. सिंथेटिक्स	94.00	45.50	91.00	6.00 +
काइनेटिक इंजी.	410.00	161.25	342.50	3.75 --
किर्लोस्कर क्युमिस	100.00	48.00	100.00	21.25 +
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	325.00	—
लारसन-टुब्रो	148.50	75.50	132.50	2.50 +
लिप्टन	84.00	52.00	82.00	5.00 +
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	15.00	1.00 +
मदुरा कोट्स	95.00	59.00	95.00	1.00 +
महिंद्रा-महिंद्रा	120.00	48.50	117.50	2.00 —
मिल्क फूड	290.00	72.50	245.00	10.00 --
मोटर इंडस्ट्रीज	700.00	447.50	650.00	—
मुकुंद आयरन	128.00	72.50	128.00	13.00 +
नेशनल ऑर्गेनिक	990.00	390.00	935.00	25.00 +
निरलॉन	16.00	5.00	13.00	0.50 +
ओरके सिल्क मिल्स	51.00	17.00	44.00	4.50 +
पेंट्को इलेक्ट्रॉनिक्स	40.00	24.50	33.50	2.00 +
फाईजर	90.00	50.00	86.00	7.00 +
प्रीमियर ऑटो	58.00	23.00	55.50	—
रैनबेक्सी	120.00	68.00	85.00	10.00 +
रेमंड	96.00	41.50	67.00	3.00 +
रिलायंस इंडस्ट्रीज	231.00	69.00	173.50	3.50 —
शां वैलेस	132.00	50.50	87.00	5.50 +
श्रीराम फाइबर्स	67.00	32.50	64.50	8.75 +
एसकेएफ बैयरिंग्स	2420.00	1058.00	2350.00	50.00 +
सीमेंस इंडिया	116.00	56.00	103.00	7.00 —
स्पिक	68.00	23.50	65.50	12.00 +
टाटा स्टील	1097.50	568.75	1076.50	29.00 +
टेल्को	785.00	340.00	762.50	27.50 +
वोल्टास	580.00	225.00	530.00	80.00 +
वीमको	30.00	11.00	27.50	1.50 +
विम्को आर्गेनिक	143.00	75.00	126.00	4.00 —
वीडियोकॉन इंडिया	70.00	18.00	60.00	2.00

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिकी मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	12.9540	12.8192
आस्ट्रिया	शिलिंग	100	1.2457	1.2285
बहरीन	दीनार	1	40.2546	40.0000
बांग्लादेश	टका	100	48.7528	48.6021
कनाडा	डालर	1	12.5090	12.3360
डेनमार्क	क्रोना	1	2.2665	2.2418
मिस्र	पौंड	1	6.6921	6.6030
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.5974	2.5316
हांगकांग	डालर	1	1.9449	1.9256
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0890	0.8000
ईरान	रियाल	100	22.32	22.00
इटली	लीरा	100	1.1117	1.0620
जापान	येन	100	12.5780	12.2699
केन्या	शिलिंग	1	0.8432	0.8010
कुवैत	दीनार	1	54.2622	54.000
मलेशिया	डालर	1	5.6897	5.6320
मारीशस	रुपया	1	1.1260	1.0921
नेपाल	रुपया	1	0.6326	0.6100
हालैंड	गिल्डर	1	7.7538	7.6702
पाकिस्तान	रुपया	1	0.8210	0.7528
सिंगापुर	डालर	1	7.7944	7.743
स्पेन	पेसो	1	0.1040	0.840
श्रीलंका	रुपया	1	0.4670	0.4422
स्वीडन	क्रोना	1	2.5055	2.4769
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	10.4013	10.2926
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1800	0.1600
थाईलैंड	बहत्त	100	57.8220	57.6020
ब्रिटेन	पौंड	1	27.4311	27.2889
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	15.1860	15.0378
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	4.0000	3.90
सोवियत संघ	रूबल	1	18.2201	18.0860
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.8731	8.6505

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 21.11.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पचड़े में पड़ा प्रस्ताव

1000 करोड़ रु. की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पहले ही काफी हंगामा मच चुका है. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की नई पाइप लाइन बिछाने की इस योजना के भविष्य पर जल्दी ही फैसला होने वाला है. उम्मीद है कि आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव लवराज कुमार जल्दी ही सरकार को सौंप देंगे.

सात साल पहले बनी 'वेस्टर्न ऑफशोर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान' नामक यह योजना बांबे हाई को हजीरा और उरण से पाइप लाइन से जोड़ने की है. यह मौजूदा पाइप लाइन की शाखा होगी. इसके पक्ष में सबसे पहले आयोग ने तर्क दिया कि मौजूदा पाइप लाइन दुश्मन के विमानों का निशाना बन सकती है या प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो सकती है.

सरकार ने रक्षा विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा किया. उनकी राय थी कि तेल की खुदाई करने वाले प्लेटफार्म और पनडुब्बी के लंगर डालने वाली तैरती व्यवस्था की तरह पाइप लाइन पर भी खतरा हो सकता है. इसके बाद आयोग ने दलील दी कि हाल में मिले तेल और गैस ले जाने के लिए नई पाइप लाइन की जरूरत होगी. इसी समय पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड ने इस मसले को एक समिति के हवाले कर दिया.

आयोग ने इस परियोजना के बारे में दो बार अंतरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित कीं लेकिन सरकारी मंजूरी न मिलने से इन निविदाओं को तुरंत वापस ले लिया गया. अब आयोग सरकारी मंजूरी मिलने के इंतजार में बैठा है.

चार्ट बी.के. शर्मा

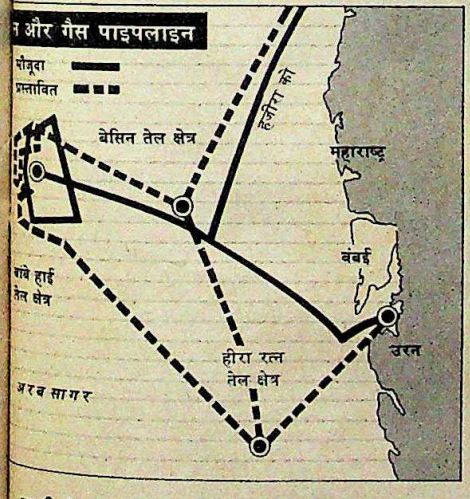

सोने का भंडार: मोल कम आंका गया

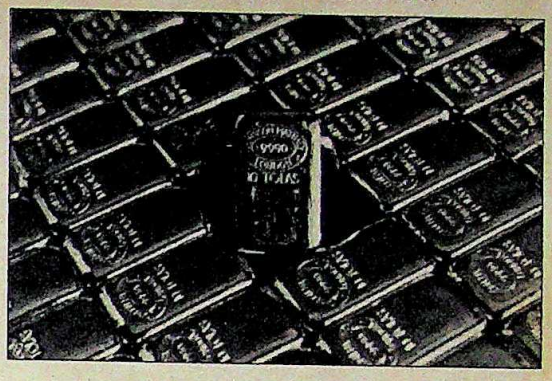

भंडार भरा रहे

क्या विदेशी मुद्रा के भंडार के बारे में की जा रही चिंता व्यर्थ है? शायद, हां. रिजर्व बैंक देश के सोने के सुरक्षित भंडार को मात्र 274 करोड़ रु. का मान रहा है.

बैंक ने 10 ग्राम सोने की कीमत 84 रु. ही मानकर यह आंकड़ा निकाला है जबकि बंबई में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 3150 रु. और लंदन में इसकी कीमत 1924 रु. है.

अगर सरकार यह सोना लंदन में बेचे तो उसे 6,253 करोड़ रु. मिल सकते हैं. बंबई में तो 10,230 करोड़ रु. मिल जाएंगे.

यूरोपीय घटनाओं से चिंता

यूरोप की घटनाओं से भारतीय व्यापारियों और सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं. यूरोपीय आर्थिक समुदाय के दर्जन भर देश 1992 तक आपसी व्यापार और वित्तीय मामलों में सारे प्रतिबंध हटाने की बात पर गौर कर रहे हैं. इससे भारतीय निर्यातक गंभीर मुश्किलों में फंस जाएंगे.

भारतीय-उद्योग जगत के प्रमुख संगठन एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज की हाल की बैठक में यह मुद्दा भी उठा. फिर चेंबर ने इसे वाणिज्य मंत्रालय के सामने उठाया. यूरोपीय संसद के भारत आए सदस्यों ने पिछले पखवाड़े पत्रकारों को बताया कि भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आर्थिक रिश्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर व्यापारी संतुष्ट नहीं हुए.

'प्रोजेक्ट 1992' नामक यह एकीकरण योजना लागू होने का मतलब होगा सदस्य देशों द्वारा एक ही साथ खरीद. भारतीय निर्यातकों का कहना है कि अफ्रीकी, कैरेबियाई और प्रशांत क्षेत्र के देशों की तुलना में यूरोपीय बाजार में पहुंचना उनके लिए तो अभी भी मुश्किल है. वजह यह है कि भारतीय निर्यात का अधिकांश हिस्सा 'सामान्यीकृत पसंद व्यवस्था' नामक समझौते से नियंत्रित होता है. इसके विपरीत अफ्रीकी, कैरेबियाई और प्रशांत क्षेत्र के देश 'लोम सम्मेलन' के तहत आते हैं जिससे उन्हें यूरोपीय बाजार में बिना सीमा शुल्क चुकाए पहुंचने की सुविधा मिल जाती है.

आखिर राह खुल गई

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव के.पी.पी. नांबियार का उत्तराधिकारी ढूंढ़ने के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव बी.जी. देशमुख के नेतृत्व में समिति नियुक्त कर दी है. समिति बन जाने से यह चर्चा खत्म हो गई है कि नांबियार का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा. इसलिए अब लगता है कि बंगलूर में वे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी खोल ही लेंगे.

प्रमोद पुष्करना

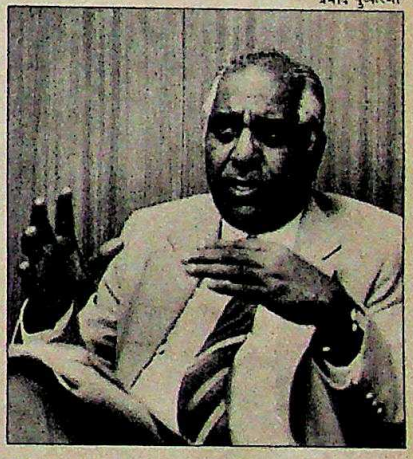

नांबियार: कार्यकाल नहीं बढ़ेगा

नांबियार का उत्तराधिकारी ढूंढ़ने के लिए समिति काफी छानबीन कर रही है. सरकारी लोगों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के नामों पर भी विचार हो रहा है. अभी नाम तय नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है, पखवाड़े भर में नामों की छंटनी हो जाएगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परमाणु ऊर्जा

विवादास्पद समझौता

सोवियत संघ के साथ अब तक का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा करार

रूस के बैले नर्तकों द्वारा पूरे भारत को चकाचौंध कर देने के बाद अब उनके वैज्ञानिकों की बारी थी. और वे लाए 2,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा. पिछले पखवाड़े भारत ने रूस के साथ जिस परियोजना के मसौदे पर दस्तखत किए वह अब तक की सबसे बड़ी और देश के चार दशक पुराने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की सबसे विवादास्पद परियोजना है. परमाणु वैज्ञानिकों ने इसके विरोध में कई प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं.

मगर सरसरी तौर पर सब कुछ 'खराशो' (ठीकठाक) ही लगता है. सोवियत संघ 1,000 मेगावाट के दो भीमकाय परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सहमत हो गया है. उसने भारत को 3.2 अरब रूबल (7,000 करोड़ रु.) का उदार कर्ज देने के अलावा उसका परमाणु कचरे का सिरदर्द भी दूर कर दिया. सोवियत संघ इसे वापस लेने पर राजी हो गया है.

पर रूसी समझौते से भारत का स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम वाला संकल्प जरूर ढीला पड़ गया. शुरू में अमेरिका और कनाडा से सहयोग लेने के बाद पिछले दो दशक में भारत ने खुद परमाणु संयंत्रों का डिजाइन बनाने, उनका निर्माण करने और उन्हें चलाने की क्षमता हासिल कर ली थी. अब सोवियत संघ के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रस्ताव से इन सभी के खटाई में पड़ने की संभावना है.

परमाणु वैज्ञानिकों को अब अंदेशा है कि इस सोवियत प्रस्ताव से खेल का स्वरूप ही बदल जाएगा. एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक ऊर्जा की जरूरतों के चलते हमने सोवियत संघ को अपने 'बने-बनाए परमाणु ढांचे में दखल देने' का न्यौता दे दिया है. उनका यह अंदेशा इन रिपोर्टों से भी पुख्ता हुआ कि भारत ऐसा ही एक परमाणु संयंत्र लगाने के फ्रांसीसी प्रस्ताव पर भी गौर कर रहा है. एक परमाणु विशेषज्ञ का तो यहां तक मानना है कि "विदेशी सहयोग की इस बाढ़ में हमारे देसी परमाणु कार्यक्रम जल्द ही बह जाएंगे."

यह भी कहा जा रहा है कि प्रस्तावित सोवियत परमाणु संयंत्रों में भारत द्वारा विकसित तकनीक से बिलकुल ही अलग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है (देखें चार्ट). माना जा रहा है कि दोनों तकनीकों के घालमेल से देश के परमाणु कार्यक्रम का कबाड़ा हो जाएगा. देश की अपनी परमाणु परियोजनाओं के लिए जरूरी पैसा और श्रम शक्ति अब रूसी संयंत्र चलाने के लिए लगने लगेगी. पर सरकार की ओर से बड़ी सतर्कतापूर्ण प्रतिक्रिया मिली जो समझौते के पक्ष में जाती है. परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन कहते हैं, "हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जितना स्वावलंबन चाहते थे, उतना हमने हासिल कर लिया है. अब हम इसे नहीं खोने वाले." उन के लिए मुख्य समस्या देश में ऊर्जा की भारी तंगी दूर करना है. केंद्रीय विद्युत

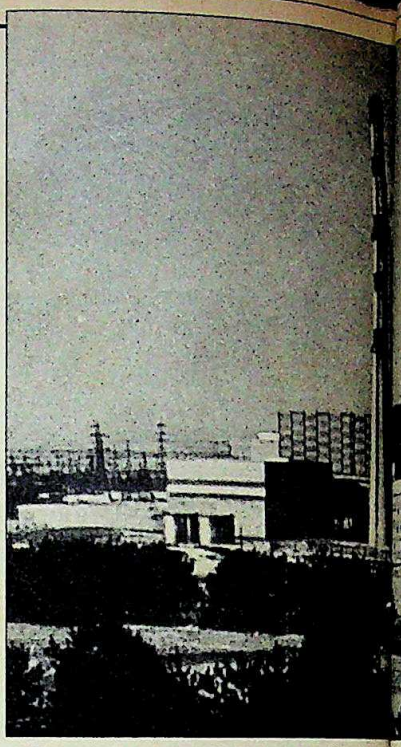

प्राधिकरण का कहना है कि ऊर्जा की मौजूद इस लि
20 फीसदी तंगी 1995 तक रहेगी. इसके कर्षक है
अलावा संसाधनों की भी भारी कमी है बिजली के
केंद्रीय ऊर्जा सचिव एस. राजगोपाल कहते जनाओं क
हैं, "सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता तुरंत शामिल
सस्ती ऊर्जा हासिल करना है."

परमाणु बिजलीघर

परमाणु ऊर्जा रिएक्टर यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन से निकली ऊर्जा का उपयोग पानी को उबालने में करते हैं. इससे पैदा भाप से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है. इसमें तीन मुख्य चीजें होती हैं: ईंधन (आम तौर पर यूरेनियम डाईऑक्साइड की गोलियां); यूरेनियम को नि

रेखाचित्र: बी.के. शर्मा

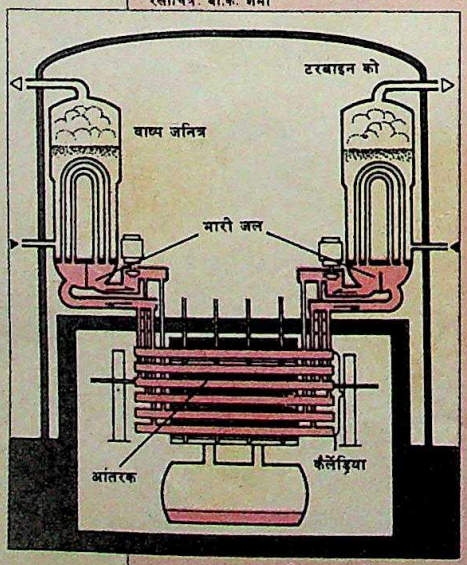

उच्च दाब भारी जल रिएक्टर

भारतीय तरीका

ईंधन
0.7 फीसदी यू-235 वाले प्राकृतिक यूरेनियम विखंडनीय समस्थानिक संशोधित किए जाते हैं.

रिएक्टर आंतरक
कैलेंड्रिया नामक पात्र की दाब नलियों में पेंसिल आकार वाली ईंधन की छड़ें डाली जाती हैं.

मॉडरेटर
न्यूट्रॉन कणों की गति कम करने के लिए सर्किट में भारी जल का उपयोग होता है.

शीतलक
विखंडन के समय निकले ताप को सोखने और स्टीम जेनरेटर तक पहुंचाने के लिए भारी का इस्तेमाल होता है.

संरोधन
कंकरीट की दोहरी कवच.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

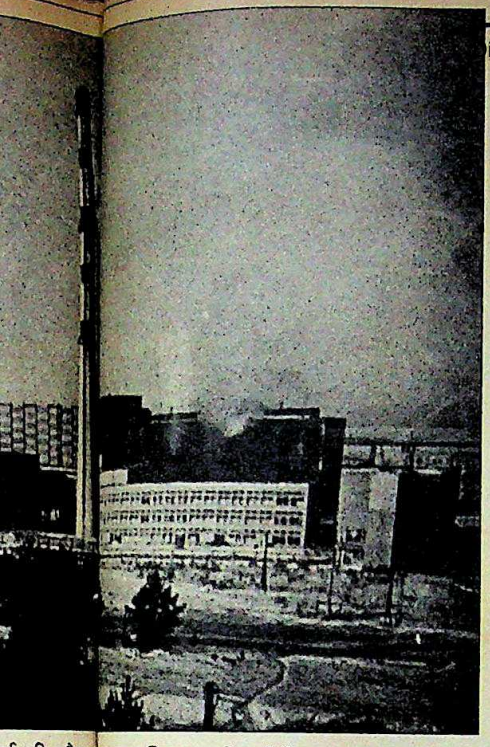

र्जा की मौजूद इस लिहाज से सोवियत प्रस्ताव काफी रहेगी. इसकाकर्षक है. इसमें कुल 6,000 मेगावाट ारी कमी हैजली के लिए ताप और पनबिजली परि- गोपाल कहतोजनाओं को कर्ज और तकनीकी मदद देना ामिकता तुरंतो शामिल है. और परमाणु गठबंधन के ामले में डॉ. श्रीनिवासन के मुताबिक, "रूस

माणु बिजपादन

उपयोग पारंतर विखंडन के लिए ठोस या तरल मॉडरेटर; विखंडन के समय पैदा होने वाले ताप को जाती है. इसर उसे स्टीम जेनरेटर तक पहुंचाने वाला शीतलक; और यूरेनियम की विखंडन ां); यूरेनिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था यानी संरोधन

सोवियत तरीका*

यूरेनियम रेनियम को रिएक्टर में डालने से पहले यू-235 की जाते हैं. ात्रा 3-5% बढ़ाने के लिए समृद्ध किया जाता है.

ों में पेंसिल स्पात के तिमंजिला दाब पात्र में ईंधन की छड़ें ती हैं. री जाती हैं.

लिए अ के जल का उपयोग होता है. है.

खने और ॉडरेटर वाला जल ही शीतलक के रूप में प्रयोग ए भारी ता है.

स्पात के साथ कंकरीट की चार फुट मोटी परतें.

*जो रिएक्टर भारत को मिला

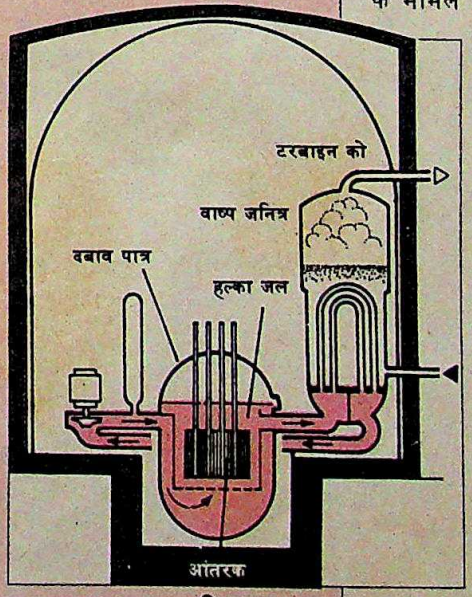

उच्च दाब जल रिएक्टर

सोवियत परमाणु संयंत्रः विवादास्पद सौदा

नवीनतम तकनीक कम ब्याज दर पर दे रहा है. सौदे की शर्तें ऐसी हैं कि हमारी नाभिकीय स्वतंत्रता पर कोई आंच न आए. कुल मिलाकर यह बढ़िया प्रस्ताव है."

रूस के हाथों 'बिक जाने' के अंदेशे को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने सौदे पर दस्तखत करने के चार महीने पहले ही 10 देसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी. ये नई परियोजनाएं 1999 तक पूरी हो जाएंगी. इनमें 4,000 मेगावाट बिजली तैयार होगी. इन पर फिलहाल 10,000 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है. सरकार ने यह भी दोहराया कि सन 2001 तक देसी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन इस समय के 1300 मेगावाट से बढ़कर 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगा (देश के छह परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिलहाल 2.5 फीसदी बिजली पैदा कर रहे हैं. सन 2001 तक इनकी क्षमता 10 फीसदी हो जाने की उम्मीद है).

इस संकल्प से सोवियत समझौते के कारण वैज्ञानिकों में उभरे मतभेद फिलहाल दब गए हैं. बंबई के भाभा परमाणु ऊर्जा शोध संस्थान के निदेशक डॉ. पी.के. आयंगर कहते हैं, "सरकार द्वारा देसी स्रोतों से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के वादे से हमारी अपनी कोशिशें धीमी नहीं पड़ेंगी." पर वे यह चेतावनी भी देते हैं कि देश की श्रम शक्ति सोवियत परियोजना की तरफ नहीं लग जानी चाहिए. न ही देश की अपनी शोध और विकास परियोजनाओं पर इसका असर ही पड़ना चाहिए.

एक अंदेशा यह भी है कि इसका असर देश के फैल रहे परमाणु उद्योग पर पड़ेगा. कई महत्वपूर्ण उपकरण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, लार्सन ऐंड टुब्रो और वालचंद्र नागर इंडस्ट्रीज जैसे बड़े उद्योगों द्वारा बनाए जा रहे हैं. इन उद्योगों को डर है कि सोवियत समझौते से उनका काम बंद हो जाएगा. हाल ही में गुजरात के हजीरा में परमाणु रिएक्टर संबंधी साजो-सामान बनाने का संयंत्र लगाने वाली लार्सन ऐंड टुब्रो कंपनी भी इस समझौते से नाखुश है. टुब्रो के महाप्रबंधक ए.एम. नाइक कहते हैं, "हमें डर है कि वे किसी न किसी तरह संयंत्र आयात करने का बहाना खोज लेंगे और हमारा धंधा ठप हो जाएगा."

लेकिन परमाणु ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक एस.एल. केती को ऐसी कोई समस्या नहीं दिखती. वे कहते हैं, "कार्यक्रम का समर्थन कर रहे लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि हम पीछे नहीं लौटेंगे. न ही हम सोवियत संयंत्रों के निर्माण के लिए कोई ज्यादा संसाधन और श्रम शक्ति खर्च करेंगे." पर दूसरे इंजीनियरों को लगता है कि निगम बढ़-चढ़कर बोल रहा है. एक इंजीनियर के अनुसार, "10,000 मेगावाट की हमारी योजना काफी ऊंची है. हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे."

यह भी माना जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा के मामले में देश ने जो बहुत ही असंतोषजनक तरीके से प्रगति की है, उसी के कारण परेशान होकर सरकार ने यह फैसला लिया है. यह समझौता करके उसने अपने वैज्ञानिकों को चुनौती दे दी है ताकि वे कमर कस लें. एक परमाणु वैज्ञानिक कहते भी हैं, "यह ऐसी चेतावनी लगती है कि काम करिए, वरना..."

भारत ने जो परमाणु नीति अख्तियार की है उस पर कुछ पुनर्विचार भी चल रहा है. भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा की उच्च दाब भारी जल रिएक्टर तकनीक पर चलते हैं. इनमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है. यह तकनीक भारत के लिए उपयुक्त भी है क्योंकि यहां

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

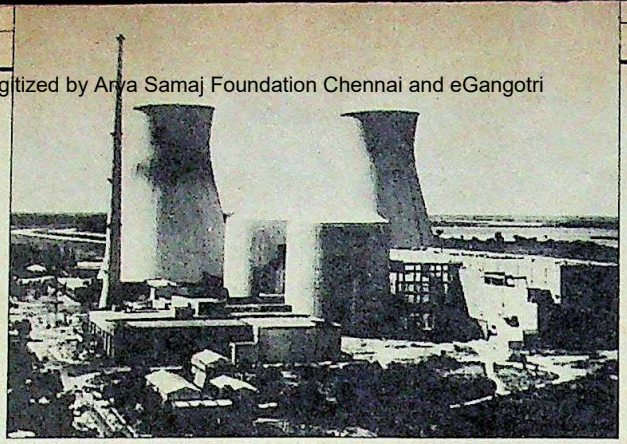

यूरेनियम अयस्क का (सीमित) भंडार है.

भारतीय परमाणु संयंत्रों की अगली पीढ़ी फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों वाली होगी. इनमें प्लूटोनियम इस्तेमाल किया जाएगा जो वर्तमान रिएक्टरों के कचरे से मिलता है. अगले चरण में थोरियम-यूरेनियम चक्र वाले रिएक्टर आ जाएंगे क्योंकि भारत के पास थोरियम का अपार भंडार है.

उच्च दाब भारी जल रिएक्टर तकनीक भारत में बहुत सफल साबित नहीं हुई है. लेकिन केती बताते हैं, "शुरुआत में हमारा ज्ञान एकदम प्रारंभिक अवस्था में था. लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है. अब देरी की उम्मीद नहीं है."

दुनिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दस फीसदी ही भारी जल वाले हैं. लेकिन यह माना जा रहा है कि इस मामले में भारत का ज्ञान तेजी से बढ़ा है. हाल ही में अनेक देशों में यूरेनियम के भंडार मिल जाने से उसके लिए मारामारी वाली स्थिति भी अब नहीं रही. पहले यह अंदेशा था कि इसकी कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी. पर ऐसा हुआ नहीं और अब इसकी कीमतों में स्थिरता आ गई है.

और इसी परिप्रेक्ष्य में सोवियत संघ से हुआ नया सौदा महत्वपूर्ण हो जाता है. सोवियत संघ हमें जो रिएक्टर देने वाला है वह उच्च दाब जल रिएक्टर तकनीक पर आधारित है, जिसका दुनिया के 60 फीसदी परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल होता है. इसमें समृद्ध यूरेनियम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है (लेकिन भारत के पास यह तकनीक नहीं है). यूरेनियम के और भंडार मिलने के बाद ऐसे रिएक्टर आर्थिक रूप से परेशानी का कारण नहीं बनेंगे. परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. दे कहते हैं, "दूसरी किस्म की तकनीक के लिए हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए. क्योंकि अगर हमारी मौजूदा तकनीक अपने चरम पर पहुंच गई तो फिर हमारे सामने दूसरा रास्ता चुनने की सुविधा तो कम-से-कम रहेगी ही. और इसी मामले में सोवियत संयंत्रों से मदद मिलेगी."

"देश के संसाधन रूसी परियोजना में नहीं लग जाने चाहिए और न ही शोध व विकास परियोजनाओं पर इसका असर पड़ना चाहिए"

डॉ. पी.के. आयंगर
निदेशक, भाभा परमाणु ऊर्जा शोध संस्थान

"हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जितना स्वावलंबन चाहते थे, उतना हमने हासिल कर लिया है. अब हम इसे नहीं खोने वाले"

डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन
अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग

कुछ वर्ष पहले ऐसी बातें बेमानी लगतीं थीं पर अब देश के परमाणु वैज्ञानिकों में व्यावहारिक समझदारी बढ़ रही है. भारत के परमाणु विकास की राह में बाधाओं को अभी दूर नहीं किया जा सका है. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक के मामले में कुछ सफलताएं मिली हैं पर इनकी क्षमता सिद्ध होनी अभी बाकी है. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक सी.बी. सुंदरम कहते भी हैं, "ऐसे रिएक्टरों की खरीद से दूसरी तकनीक के लिए रास्ता खुलेगा."

सोवियत संघ से हुए सौदे के ये पहलू तो अच्छे हैं. पर इसके अनेक बुरे पहलू भी हैं. अपने परमाणु संयंत्रों के ईंधन के लिए भारत हमेशा दूसरे देशों पर आश्रित रहा है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मौजूदा समीकरण पलटने से हम राम भरोसे रह जाएंगे.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जिस आसानी से भारत की 'सीमित सुरक्षा' वाली शर्त को मान लिया उससे संदेह होता है कि यह अपनी तकनीक बेचने के लिए महाशक्तियों का नया खेल है. सोवियत संघ के लिए तो यह सौदा बहुत बड़ी उपलब्धि है. हाल तक उसके प्रस्तावों पर भारत का रुख बहुत ठंडा था. परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजा रमन्ना समेत अनेक बड़े वैज्ञानिक ऐसे सौदे के खिलाफ थे. उनका मानना था कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए यह बाधक होगा.

सोवियत प्रस्ताव ने कई और सवाल खड़े किए हैं. ऐसे रिएक्टर लगाने में कितना खर्च आएगा, अभी यह अनुमान नहीं लगाया गया है. योजना संबंधी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकेगा. तभी मालूम पड़ेगा कि ऐसे रिएक्टर लगाना उचित होगा या नहीं.

इस बीच एक और झंझट उठा है. नया रिएक्टर लगाने के लिए तमिलनाडु के कूडनकुलम को चुने जाने के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो रहा है. अनेक प्रमुख नागरिक अपने पड़ोस में '1000 मेगावाट का टाइम बम' बनने के खिलाफ बयान जारी कर चुके हैं. डॉ. श्रीनिवासन मानते हैं कि यही जगह सबसे अच्छी है और सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. और यह भी कि दक्षिणी राज्यों में बिजली की कमी है और यहां नए बिजलीघर लगाने से उन्हें फायदा होगा.

देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी भाभा ने एक बार कहा था, "बिजली का अभाव महंगा पड़ता है." पर सोवियत संघ की मार्फत आने वाली बिजली इस अभाव को दूर करने में महंगी पड़ेगी या नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. —**राज चेंगप्पा, बंबई में और अमरनाथ के. मेनन, मद्रास में**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आंध्र प्रदेश

प्रचार का जादुई नुस्खा

रामराव के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाएंगे जादूगर

गांववालों की भीड़ काली 'बो' टाई और कोट पहने एक युवक को घेरे खड़ी है. यह युवक बाजा बजने के साथ एक सिलिंडर लेता है और उसे उलट देता है यह दिखाने के लिए कि सिलिंडर खाली है. फिर वह दो रुपए का एक नोट उसमें रखता है और एक काली छड़ी उसके चारों तरफ तीन बार घुमाता है. फिर वह उस छड़ी को बाएं से दाएं हाथ में ले लेता है और उस सिलिंडर को एक खाली प्लेट में उलट देता है. गांववाले यह देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि सिलिंडर में से चावल गिरता है. प्रतापसिंहरम गांव के इस 27 वर्षीय युवक विष्णुवर्द्धन रेड्डी ने अपनी इस जादूगरी से यह संदेश भी दिया कि "सरकार की तरफ से यह गरीबों को दो रुपए का उपहार है." गांववाले खुशी में ताली बजाते हैं.

आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव के जादुई भगवे चोले से निकली यह एक नई भेंट है. रेड्डी उन चुने हुए 58 जादूगरों में से एक हैं जो 1 नवंबर से गांव-गांव जाकर तेलुगु देशम सरकार का प्रचार कर रहे हैं और उसकी प्रगतिशील छवि बना रहे हैं. प्रचार के तिकड़मों में रामराव भला किससे पीछे रहने वाले हैं!

रामराव को गांव-गांव घूमने वाले ऐसे जादूगरों के इस्तेमाल का विचार उस समय सूझा जब पिछले साल आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस के समारोहों के दौरान वे जाने-माने जादूगर बी.वी. पट्टाभि राम का एक कार्यक्रम देख रहे थे. राम ने उस दिन 'वाटर ऑफ इंडिया' वाला अपना जादू दिखाया था. उन्होंने खाली दिखने वाले एक बर्तन से पानी निकाला और फिर उसे खाली कर यह बताया कि पानी का स्रोत सूख गया. इस प्रतीकात्मक खेल का मतलब यह था कि तेलुगु गंगा परियोजना का इस्तेमाल मद्रास और सिंचाई की कमी वाले क्षेत्र रायलसीमा तक पानी पहुंचाने में किया जा सकता है, लेकिन राजनैतिक तकरार के कारण उसकी धारा सूख गई है. फिर उन्होंने एक दूसरा खाली सिलिंडर लिया और उसे उलट दिया. उसमें से कई पौधे निकले. इसका मतलब यह था कि पेड़ों को लगाने और पौधों के संरक्षण की जरूरत है.

यह सब देखकर रामराव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तेलुगु विश्वविद्यालय के कुलपति टी. दोणप्पा से कहा कि जादूगरों को प्रशिक्षित करने का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए. और एक हफ्ते के भीतर ही रामराव को इस पाठ्यक्रम का निदेशक नियुक्त किया गया. छह हफ्ते के इस पाठ्यक्रम में 10 छात्रों के पहले जत्थे की भर्ती की गई. इन लोगों की भर्ती इस बात की पुष्टि करने के बाद हुई कि वे बेरोजगार हैं, गरीब हैं, और इस कैरियर को गंभीरता से लेना चाहते हैं. हरेक को प्रशिक्षण के बाद 1,000 रु. का सामान दिया गया.

दोणप्पा इस कदम का यह कहते हुए बचाव करते हैं, "जादू प्राचीन पुस्तकों में उल्लिखित 64 कलाओं में से एक है. तेलुगु कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के प्रपत्र में यह उपयुक्त बैठता है." रामराव ने तो इस साल एक कदम आगे बढ़कर जादू को एक कला के रूप में सरकारी मान्यता भी दे दी. उन्होंने राज्य के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय की सहायता ली. और, राम को गांव-गांव जाकर जादू दिखाने वाले जादूगरों की सूची बनाने के लिए कहा गया. इन जादूगरों में नए स्नातकों के साथ दूसरे जादूगर भी शामिल थे. सूचनामंत्री वीरभद्र राव कहते हैं, "हमारा मकसद दूसरी लोक कलाओं की तरह जादू को बढ़ावा देना, ग्रामीणों का मनोरंजन करना, और शिक्षा-प्रद संदेश फैलाना है."

राम ने विस्तार से बताया, "संदेश के बारे में बातें उबाऊ होंगी. हर बाजीगरी या स्टंट विज्ञान या गणित के किसी सिद्धांत पर आधारित होता है और हम जो कुछ कर रहे हैं उसका मकसद लोगों पर एक असर पैदा करना है." राम जब भारतीय खाद्य निगम में थे तो अनाज बचाने जैसे उपायों के प्रचार के लिए वे जादू के खेलों का इस्तेमाल करते. राम ने जादूगरों के लिए एक कार्यशाला आयोजित कर उन्हें बताया कि वे लोगों को रियायती दर पर मिलने वाले चावल और प्रौढ़ शिक्षा जैसे उपायों, और राष्ट्रीय अखंडता तथा अस्पृश्यता मिटाने जैसे आदर्शों के बारे में बताएं.

अब जादूगर 'शैतान की स्लेट' का खेल भी दिखाते हैं. वे एक जोड़ा स्लेट लेकर उन्हें चारों तरफ घुमाते हैं. और स्लेट के एक

सभी फोटो : श्याम टेकवानी

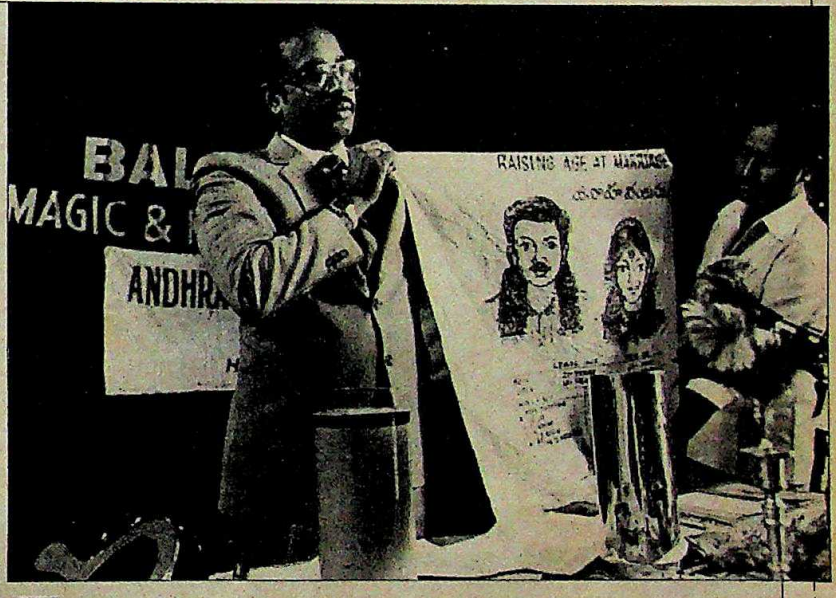

पट्टाभि राम खाली डिब्बे से एक झंडा निकालते हैं जिस पर शादी की न्यूनतम उम्र और कानून न मानने वालों को दिए जाने वाले दंड लिखे होते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचतन्त्र

पढ़ने की मौज रंगन की मस्ती

Near the river
That curves and bends,
Lived these four
Remarkable friends.

The deer, one day,
Fell in a hunter's trap.
She was found missing
When they woke from their nap.

मोड़दार बलखाती
इक नदी के पास,
रहते थे चारों
ये अनूठे यार।

एक दिन हिरनी
फंसी जाल में शिकारी के,
पता कहीं न पाया उसका
नींद से जब जागे वे।

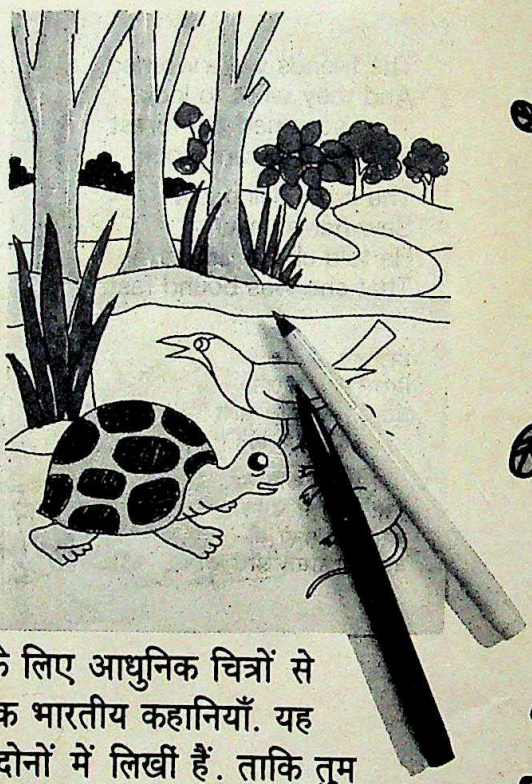

बच्चों, तुम्हारें मनोरंजन के लिए आधुनिक चित्रों से सुसज्जित कुछ पुरानी रोचक भारतीय कहानियाँ. यह कहानियाँ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखीं हैं. ताकि तुम दोनों भाषाओं का आनन्द उठा सको. रेखाचित्र विशेष रुप से बनाये गये हैं जिसमें तुम स्वयं मनपसंद रंग भर कर एक रंगीन पुस्तक तैयार कर सकते हो.

इस श्रंखला की चारों पुस्तकें वी.पी.पी. से केवल रु. 20/- में लेने के लिए अपने नाम व पते के साथ निम्नलिखित पते पर लिखिए : लिविंग मीडिया लि., डायरेक्ट मेल युनिट, थौमसन प्रेस बिल्डिंग, देहली-मथुरा रोड़, फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा).

यह पुस्तकों की श्रंखला लिविंग मीडिया इंडिया लि. के नाम चैक, मनी आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट भेजने पर भी मिल सकती है.

अभी कोई पैसे भेजने की ज़रुरत नहीं है !

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तरफ 'कूडु, गूडु, गुड्डा' (रोटी, कपड़ा और मकान) लिखा आ जाता है. लेकिन इन जादूगरों को इस बात का भी एहसास है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर देने का उलटा प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए वे अगर पांच खेल दिखाते हैं तो उनमें से एक में ही कल्याण कार्यक्रमों की बात करते हैं. और वह भी इस तरह कि दर्शक दिलचस्पी लें और समझें.

वे आमतौर पर अपने खेलों की शुरुआत जलती हुई मोमबत्ती से फूल पैदा करने या कागज के टुकड़ों को जोड़ने और हथेली से कागज के टुकड़े पैदा करने जैसी हाथ की सफाई से करते हैं. फिर वे लोगों को संदेश देने जैसे महत्वपूर्ण काम पर आते हैं. मिसाल के तौर पर, राम एक खाली सिलिंडर से एक बैनर निकालते हैं जिस पर शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित कानून और उसे न मानने पर दंड के प्रावधानों का विवरण छपा होता है.

सरकार ने जादू के इस असर के एहसास के बाद ही 58 जादूगरों को 350 रु. रोज पर महीने में चार दिन जादू का प्रदर्शन करने के लिए चुना. इसके साथ इन जादूगरों को दूसरी जगहों पर अपने निजी खेल दिखाने की भी छूट दी गई है. नवनियुक्त जादूगरों के लिए तो यह कैरियर एक अलग ही किस्म का है. स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने वाले 21 वर्षीय भद्रैया कहते हैं, "रोजी-रोटी कमाने के लिए लोगों का मनोरंजन करने से ज्यादा सम्मानजनक काम और कोई नहीं हो सकता."

तेलुगु विश्वविद्यालय के अलावा हैदराबाद में भी जादू का एक औपचारिक स्कूल है. यहां महीने में एक बार कक्षाएं लगती हैं. यहां का सालाना शुल्क 100 रुपए है. इसके अलावा आठ साल पुराना बालनंदन मैजिक स्कूल भी है. हैदराबाद की बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा के. प्रसून कहती हैं, "जादू कोई साधारण मनोरंजन नहीं है. यह एक सामाजिक अभियान है. आप इसे सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और इससे मनोरंजन कर सकते हैं." प्रसून गणित में अपनी रुचि के कारण जादू सीखने लगीं. उभरती हुई 20 महिला जादूगरों में से वे भी हैं. राम का कहना है कि इनमें से ज्यादातर शौकिया ही हैं.

विष्णुवर्द्धन रेड्डी एक खाली सिलिंडर में दो रुपए का नोट डालते हैं और जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें से चावल गिरने लगता है

जादूगर दो स्लेट दिखाता है, फिर उन्हें हवा में उछाल देता है और इस पर एक तरफ 'कूडु, गूडु, गुड्डा' (रोटी, कपड़ा और मकान) लिखा आ जाता है

जादू के खेल में रामराव सरकार की बढ़ती दिलचस्पी और दिसंबर में शुरू होने वाले विश्वविद्यालय के आगामी सत्र से खुद उनके लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं. फिलहाल राम और उनके साथी हैदराबाद और उसके आसपास के जिलों में प्रचलित 'बानामाटी' (काला जादू) के खतरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. यहां जादूगरों ने अपने खेलों में एक नया खेल शामिल कर लिया है. वे किसी दर्शक के पास से सिक्के और कील निकालकर यह बताते हैं कि काला जादू सिर्फ हाथ की सफाई है. वे भोले-भाले लोगों का शोषण करने वाले 'भगवानों' आदि का भी पर्दाफाश कर रहे हैं.

चूंकि जादू और धूर्तता के बीच की रेखा बहुत महीन होती है, इसलिए इसे दुधारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी अपने करिश्मों के बूते राज करने वाले रामराव के तरकश में एक और हथियार आ गया है. —अमरनाथ के. मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीलंका

एक इम्तिहान में कामयाब

प्रांतीय परिषद के शांतिपूर्ण चुनाव से समझौते को नया जीवन

अभी कुछ हफ्ते पहले तक भारतीय विदेश मंत्रालय के ऊपरी हलकों के लिए भी यह बात कल्पना से परे थी कि श्रीलंका के एक-तिहाई हिस्से की बागडोर किसी तमिल मुख्यमंत्री के हाथ में जा सकती है. कुछ दिनों पहले रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत भी जब यह आश्वासन दे रहे थे कि भारत-श्रीलंका शांति समझौते के वादे के अनुसार द्वीप के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सफलतापूर्वक मतदान कराया जाएगा तब वे थोड़े आशंकित भी थे. लेकिन पिछले पखवाड़े 73 सदस्यीय उत्तर-पूर्वी प्रांतीय परिषद के चुनाव से शुरू हुई राजनैतिक प्रक्रिया पूरी हो गई है. एक तमिल उग्रवादी संगठन, ईपीआरएलएफ के नेता ए. वरदराज पेरुमल के नेतृत्व में राज्य में पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल जल्द ही शपथ ग्रहण करने वाला है.

पिछले महीने तीन पूर्वी जिलों-त्रिंकोमाली, बट्टीकलोआ और अंपरई— की 35 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई. चुनाव मैदान में तीन प्रमुख दलों— ईलम पीपुल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट (ईपीआरएलएफ), श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस (एसएलएमसी) और यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी)— के 119 उम्मीदवार थे. ईपीआरएलएफ और ईलम नेशनल डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट (ईएनडीएलएफ) के गठजोड़ को 15 सीटें मिलीं. इस तरह जल्दी ही औपचारिक रूप से गठित होने वाली विधानसभा में उसे 51 सदस्यों का भारी बहुमत प्राप्त हो गया. इस बार लोगों की व्यापक भागीदारी से चुनाव की सफलता अक्तूबर में हुए पहले दौर के चुनावों के एकदम विपरीत रही. तब गठजोड़ के 36 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे क्योंकि ज्यादातर दूसरे उम्मीदवार नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं कर पाए थे. जैसा कि पंत ने 'इंडिया टुडे' को बताया, "भारत-श्रीलंका समझौते पर अमल की दिशा में हमने अपनी ओर से एक जोरदार पहल की है."

इसके साथ ही इस द्वीप के खूनी और अनिश्चित दौर में मनहूस ताकतें गलत साबित हुई हैं. चुनाव के पहले तक यही अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनाव में भारी खूनखराबा हो जाएगा. लेकिन चुनाव न सिर्फ शांति से संपन्न हो गए बल्कि तमाम धमकियों और बहिष्कार की अपीलों के बावजूद सात लाख में से 60 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले. चुनाव का विरोध करने के लिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) और जनता विमुक्ति पेरुमना (जेवीपी) अचानक दोस्त बन गए थे और उन्होंने वोट डालने वालों के लिए जानलेवा धमकियां जारी की थीं. बहरहाल, कई लोगों को वोट देने के लिए लंबी कतारों में चार-पांच घंटों तक खड़े देखा गया.

भारतीय शांति सेना की टुकड़ियों और कमांडो सैनिकों की सुरक्षा का पूरा लाभ उठाते हुए महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया. बट्टीकलोआ के एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, "मैं अपना वोट डालने के लिए शाम तक इंतजार करूंगा. पहली बार हमें अपनी पसंद के शासकों को चुनने का मौका मिला है." श्रीलंका में शांति सेना के 50,000 सैनिकों के प्रमुख ले. जनरल अमरजीत कालकट ने कहा, "शांति सेना ने अपना काम पूरा कर दिया है. व्यवस्था लोकतांत्रिक ताकतों के हाथ आ गई. यह भारत-श्रीलंका समझौते के विरोधियों की करारी हार है." पिछले 14 महीनों में शांति सेना के हाथ लगी नाकामियों और आलोचनाओं के बाद शांतिपूर्वक चुनाव करवाने की सफलता पर उनका यह बयान जायज ही है.

प्रांतीय चुनाव शांति सेना की क्षमता और रणनीति की अंतिम परीक्षा बन गए थे. चुनाव के विरोधियों पर काबू पाने के लिए शांति सेना की कार्ययोजना को 'ऑपरेशन महान कर्तव्य' नाम दिया गया. मतदान से एक हफ्ते पहले शांति सेना ने द्वीप के पूर्व

मतदान केंद्र पर कतार: बहिष्कार नहीं

सभी फोटो : श्याम टेकवानी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...से में 300 से अधिक गांवों और शहरों ...सभी रास्तों पर निगरानी कड़ी कर दी थी. ...कालकट त्रिकोमाली में शानदार ट्रक पर ...ती चलती-फिरती चौकी में बैठे निगरानी ...भियान का संचालन कर रहे थे.

मतदान के बाद शाम 4 बजे कालकट ने ...टलाइन (टेलीफोन) से नई दिल्ली में ...सेनाध्यक्ष वी.एन. शर्मा को सूचित किया ...'ऑपरेशन महान कर्तव्य' को महान ...लता मिली है. बिजली की तरह शर्मा ने ...रन पंत को इसकी सूचना दी.

भारत सरकार के लिए तो जैसे राजनैतिक ...रा ही मिल गया. सत्ता दल ने शांति सेना ...सफलता को भुनाने में कोई वक्त जाया ...किया. मतदान संपन्न होने के 24 घंटे ...ही विदेशमंत्री पी.वी. ...सिंह राव ने लोकसभा में कहा,

चुनाव के लिए शांति सेना के 'ऑपरेशन महान कर्तव्य' की सफलता पर अगर उसके नायक कालकट नाज करते हैं तो ठीक भी है

...बयान में कोई अतिशयोक्ति ...है. मुझे पक्का यकीन है कि ...सदन उन तमिल दलों को ...ई देने में मेरा साथ देगा, जिन्होंने शांति ...लोकतंत्र के लिए अपूर्व साहस और ...शिता का परिचय दिया है.''

...पक्ष पहले तो हैरान रह गया पर उसके ...उसने सावधानी बरतते हुए अपनी ...क्रिया जाहिर की. द्रमुक और तेलुगु देशम ...रकार को चेतावनी दी कि तात्कालिक ...ता के बावजूद श्रीलंका में शांति सेना ...मौजूदगी उलटा असर भी दिखा सकती है. ...में तेलुगु देशम के नेता पी. उपेंद्र ने ...''हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ...श्रीलंका से शांति सेना को हटने के लिए ...जाए, नई परिस्थिति से शांति सेना की ...की का रास्ता खुलेगा.'' द्रमुक के तेज-...राज्यसभा सदस्य वी. गोपालस्वामी ने ...''भारत सरकार पूरब में एक कठपुतली ...सरकार बनाने की कोशिश में है. उसे ...ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए, न कि उनका सफाया करने की कोशिश. राव का बयान बंदूक की नोंक पर कराए गए एक अलोकतांत्रिक और फरेबी चुनाव को जायज ठहराने की घालमेल भर है.''

हालांकि निर्वाचित उम्मीदवारों के राजनैतिक चरित्र और मतदाताओं को शांति सेना द्वारा दी गई पूर्ण सुरक्षा से यह सवाल उठा है कि चुनाव भारतीय प्रभावों से सचमुच कितना मुक्त रहा है, पर चुनाव हुआ यही अपने आप में इस बात का महत्वपूर्ण संकेत है कि समझौते की अकाल मृत्यु की बातें अतिशयोक्ति ही हैं. शांति सेना के दृढ़ निश्चय और जयवर्द्धने व राजीव के पूर्ण समर्थन के बिना चुनाव नहीं हो पाते. भारत सरकार श्रीलंका में दिसंबर में होने वाले राष्ट्रपति

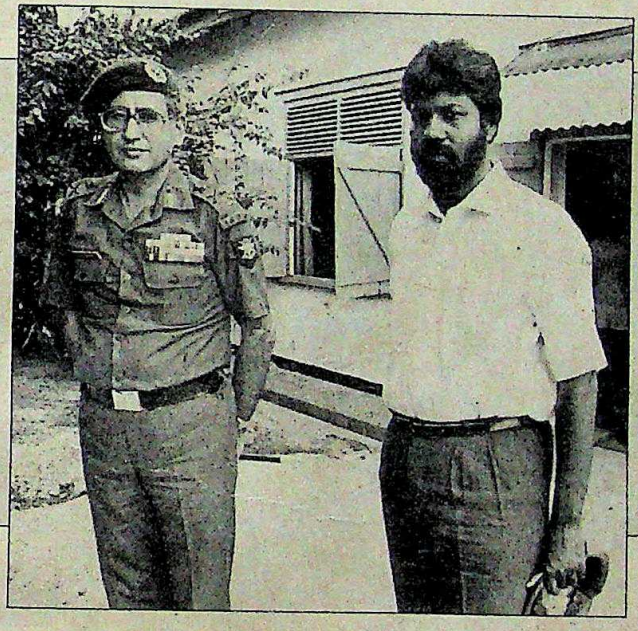

पद्मनाभ के साथ कालकट : सहयोग

चुनावों के पहले ही प्रांतीय चुनाव करवाने के प्रति दृढ़ थी ताकि नया राष्ट्रपति स्थानीय दबाव के चलते चुनाव को स्थगित करके समझौते को एकदम बेमानी ही न कर दे.

दरअसल, इस नाजुक मोड़ पर चुनाव का विरोध भारतीय अफसरशाही के कुछ तबकों के साथ ही श्रीलंका सरकार की ओर से भी उभरा था. श्रीलंका में इसके विरोध का मुख्य कारण यह आशंका थी कि इससे जातीय बंटवारे को शह मिलेगी और तमिल प्रांतीय सरकार पर श्रीलंकाई प्रशासन का नियंत्रण काफी हद तक घट जाएगा.

उधर, भारतीय विदेश विभाग को आशंका थी कि चुनावों से शांति सेना और एलटीटीई छापामारों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ जाएगा. आशंका निराधार नहीं थी क्योंकि एलटीटीई ने चुनाव न करवाने देने की कसम खा रखी थी. उसने पूरे प्रांत में ऐसे पर्चे बांटे थे जिनमें अपने कार्यकर्ताओं को 12 नवंबर से 17 नवंबर के बीच हर रोज प्रत्येक गांव के कम-से-कम पांच लोगों की हत्या का निर्देश दिया गया था. भारतीय विदेश विभाग ने इस धमकी को गंभीरता से लिया. लेकिन रक्षामंत्री पंत और उच्चायुक्त मणि दीक्षित ने, जो विदेश विभाग की आशंकाओं से सहमत नहीं थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आश्वस्त कर दिया. शांति सेना को चुनाव के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया.

हर तरफ से विरोध हो रहा था. श्रीलंका के नौकरशाह और राजनीतिक भी खिलाफ थे. वहां के चुनाव आयोग ने भी इस दलील के साथ चुनाव संपन्न करवाने में अपनी असमर्थता जाहिर की कि

ईपीआरएलएफ के प्रमुख पद्मनाभ यह मानने से नहीं हिचकते कि कुर्सी के साथ ही अपनी निजी सुरक्षा के लिए वे भारतीय शांति सेना पर ही निर्भर हैं

उसके कर्मचारी असुरक्षित महसूस करेंगे. इस नाजुक स्थिति से निबटने के लिए कोलंबो में कई बैठकें हुईं. राष्ट्रपति जयवर्द्धने की अध्यक्षता में हुई इन बैठकों में रक्षा सचिव जनरल अत्तिगले, मंत्री ललित अतुलतमुदांली व जामिनी दिशानायके, दीक्षित और कालकट भी शरीक हुए.

राष्ट्रपति जयवर्द्धने को चुनाव की जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित आदेश देना था. लेकिन जेवीपी के प्रभाव के कारण स्थानीय सरकारी कर्मचारियों ने मतदान ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया था. 2660 मतदान अधिकारियों में से सिर्फ 587 ही ड्यूटी पर आए और उनमें से आधे लोगों को तो शांति सेना के विमान से पहुंचाना पड़ा.

लेकिन इस मुख्यतः सैनिक सफलता के दीर्घकालिक राजनैतिक नतीजों के बारे में अभी भी अनुमान नहीं लग पा रहा है. निर्वाचित उम्मीदवारों का भारत प्रेम जगजाहिर है. चूंकि इस चुनाव में किसी तरह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नक्शा: बी.के. शर्मा

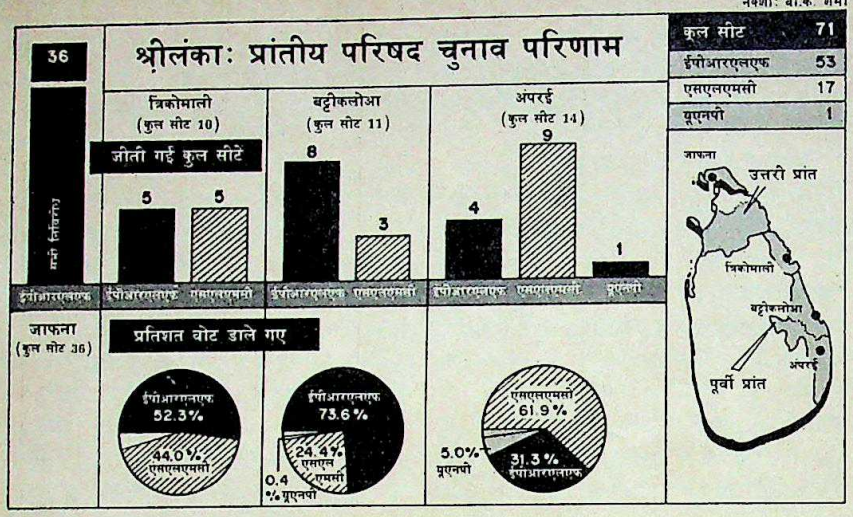

का प्रचार नहीं किया गया इसलिए इसकी लोकतांत्रिक प्रामाणिकता पर जायज सवाल उठाए गए हैं. लेकिन निर्वाचित उम्मीदवार इस सचाई से कतई इनकार नहीं करते कि वे अपनी कुर्सी के साथ ही अपनी निजी सुरक्षा के लिए शांति सेना पर ही निर्भर हैं. ईपीआरएलएफ के प्रमुख के. पद्मनाभ ने कबूल किया, "शांति सेना की भूमिका चुनाव के साथ ही खत्म नहीं हो गई है. उसे उत्तर-पूर्व में पूरी शांति कायम करनी होगी और प्रांतीय सरकार के लिए अधिक अधिकार प्राप्त करना होगा."

'अधिक अधिकार' की लड़ाई, जैसा कि पद्मनाभ कहते हैं, नई दिल्ली और कोलंबो के बीच भविष्य में तनातनी के जोखिम के साथ लड़ी जानी है. सिंहली उग्रवादियों को शांत करने के लिए श्रीलंका सरकार तमिल-शासित प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार देने की हर कोशिश का विरोध करेगी. साथ ही, एलटीटीई को बेअसर करने के लिए ईपीआरएलएफ श्रीलंका के साथ संघर्ष तेज कर सकता है. ईएनडीएलएफ के उपमहासचिव पी. मनोहरन कहते हैं, "अगर श्रीलंका सरकार इस क्षेत्र में शांति चाहती है तो शांति रहेगी लेकिन अगर वह संघर्ष चाहती है तो हम हथियार उठाने से हिचकेंगे नहीं."

सरकार के गठन की प्रक्रिया में समस्याएं और जटिल हो जाएंगी. पहले तो जयवर्द्धने राज्यपाल की नियुक्ति में देरी कर सकते हैं. समझौते के अनुसार तमिल-बहुल इलाकों में राज्यपाल कोई सिंहली ही होना चाहिए.

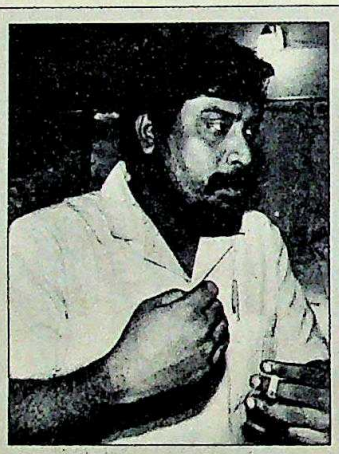

"लोगों ने तमिल सरकार के गठन के पक्ष में फैसला दिया है. हमें ज्यादा अधिकार देने में देरी की गई तो टकराव की नौबत आ सकती है"

ए. वरदराज पेरुमल
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री

लेकिन उत्तर-पूर्वी प्रांत के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, ईपीआरएलएफ नेता ए. वरदराज पेरुमल कहते हैं, "लोगों ने तमिल सरकार के गठन के पक्ष में फैसला दिया है. हमें ज्यादा अधिकार देने में देरी की गई तो टकराव की नौबत आ सकती है."

ईपीआरएलएफ की प्राथमिकता भूप्रबंध अधिकार हासिल करने और उत्तर-पूर्वी प्रांतों के औपचारिक विलय के लिए केंद्र सरकार से जूझना है. हालांकि इसका आखिरी फैसला जनमत संग्रह से ही होगा पर इसकी उम्मीद कम ही है कि केंद्र इस मांग को मान लेगा, क्योंकि तब सिंहली आबादी उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को छोड़ कर भागने लगेगी.

इसलिए ईलम नेताओं और शांति सेना की तात्कालिक प्राथमिकता इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना है. लेकिन इसमें बहुत पेंच हैं. प्रांतीय परिषद के चुनाव पूरी तरह सांप्रदायिक आधार पर ही लड़े गए. मुसलमानों ने मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट दिया, और तमिलों ने तमिल उम्मीदवारों को एसएलएमसी के नेता एम. एच. अशरफ ने कहा कि उनकी पार्टी मुस्लिम इलाकों के लिए एक अलग परिषद की स्थापना के लिए लड़ेगी.

उधर, एलटीटीई के चीतों का जंगलों में अभी भी राज है. पर्यवेक्षकों का मानना है कि नई व्यवस्था में तमिल चीतों को शामिल करने की गंभीर कोशिश करके शांति सेना की वापसी का रास्ता नहीं खोला जाता तो चुनाव की सफलता बेमतलब ही साबित हो सकती है. इसी एहसास के तहत ईपीआरएलएफ और भारत सरकार दोनों ने ही चुनाव के बाद सुलह-सफाई वाले बयान दिए हैं.

लोकसभा में राव ने कहा, "मैं फिर एलटीटीई से आग्रह करूंगा कि जिस तमिल जनता के प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं, उसका उन्हें आदर करना चाहिए और हिंसा की राह छोड़ देनी चाहिए." उधर त्रिकोमाली में ईपीआरएलएफ के एक उम्मीदवार टी. जॉर्ज ने कहा, "हमारा दुश्मन श्रीलंका की नस्लवादी सरकार है. हम यही चाहते हैं कि एलटीटीई हमसे लड़ना छोड़कर दुश्मन से लड़ने में हमारा साथ दे."

चुनाव के समाप्त होने के बाद अब भविष्य में कभी भी इस तरह की समस्या पेश आ सकती है जिससे जूझना पड़ेगा. कोलंबो में कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो भारत-श्रीलंका समझौते की विरोधी हो तो निश्चित रूप से भारतीय कूटनीति के लिए वह परीक्षा की घड़ी होगी.

लेकिन फिलहाल तो खुश होने के कई कारण हैं. चुनावों के कारण एलटीटीई का राजनैतिक विकल्प उभर आया है. पेरुमल के नेतृत्व में बनी सरकार में मुस्लिम समुदाय का भी एक सदस्य है. मतदान भले ही एकपक्षीय रहा हो मगर यह शांति के पक्ष में ही था. समझौते पर दस्तखत के बाद उस दिशा में यह पहला बड़ा कदम है और अब पहली बार भारत-सरकार श्रीलंका में शांति सेना की उपस्थिति को जायज ठहरा सकती है.

लेकिन यह खुशनुमा माहौल भले ही अस्थायी हो, यह एक सबक भी दे रहा है वह यह कि भारत सरकार शांति सेना पर ही निर्भर नहीं रह सकती. श्रीलंका अभी भी उसकी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

—प्रभु चावला, त्रिकोमाली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

WHEN THERE IS A NIP IN THE AIR
ESSMA ARE EVERYWHERE
SHAWLS
Woolmark
PURE NEW WOOL
Trade enquiries solicited
ESSMA WOOLLEN MILLS,
G T ROAD, PUTLIGHAR, AMRITSAR-143 001
PHONES 63252, 63245, 64921
TELEX 0384-238 ESMA IN, GRAMS 'ESSMA'

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

FUNSKOOL

MEMORY GAMES

Funskool brings to India the internationally popular Memory Games, specially designed to help your children develop their memory skills.

Funskool's Memory Games build visual recall ... as well as object, colour and shape recognition. They encourage your child to think, while providing hours of absorbing enjoyment. Besides, these games are so simple, they require no parental supervision.

And that's not all. Memory Games come in a range of 5 different and exciting sets and are designed to grow with your child.

For ages 3 - 6:
- The Original Memory
- Fronts and Backs Memory
- Animal Families Memory

For ages 5 - 8:
- Step by Step Memory
- Match and Move Memory

So bring home Memory Games. And let your child discover that learning can be fun!

Hasbro, the world's largest toy company, is now Funskool in India.

WE MAKE LEARNING FUN.

FUNSKOOL

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Allahabad.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब भला बात को कब तक छिपाएं? इसी स्तंभ में हमने सब कुछ 'छिपाया' था कि रेखा के इनकम टैक्स का मामला रफा-दफा करवा देने में अमिताभ बच्चन का नाम सिर्फ आड़ के लिए उछाला जा रहा है. असली वजह तो कुछ और है. जिन लोगों का नाम मामला रफा-दफा करवा देने में लिया गया है, उनमें सबसे प्रमुख हैं अजित पांजा. कहा जा रहा है कि रेखा को 'मुलाकात' के लिए उनके बंगले तक पहुंचाने में रेखा के एक नायक-खलनायक आशिक ने मदद की और इस तरह राजनीति में अपनी दखल का सिक्का जमाना चाहा. रेखा का काम हो गया बस! अब यह सोचना आपका काम कि किसने, किस पर, कैसे, क्या सिक्का जमाया होगा!

अनीता राज: भारी चक्कर

•••••••••••••

फिल्मों को लेट होने से बचाने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा काम निबटा देने की कोशिश हर व्यस्त गर्भवती अभिनेत्री करती है.

यही हालत अनीता राज (हिंगोरानी) की भी है और नतीजा वही हुआ जो ऐसे में होता है. गर्भवती अनीता शूटिंग पर शूटिंग करती रहीं, और 'खतरनाक' की शूटिंग से उन्हें खतरनाक हालत में बीच केंडी अस्पताल पहुंचाना पड़ा.

अनीता के अभिनेता पिता जगदीश राज भी मानसिक परेशानी में हैं. पिछले दिनों गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड की ओर से चिट्ठी आई कि फिल्मों में पुलिस अफसर की भूमिका उन्होंने सबसे ज्यादा बार निभाई है.

जगदीश राज घबरा इसलिए रहे हैं कि अब एक नया युवा अभिनेता महेश राज इस तेजी से पुलिस अफसरी (मुख्यतः टीवी सीरियलों में) कर रहा है कि किसी दिन उनका रिकार्ड टूट जाने का खतरा हो सकता है. महेश राज ने 'तूफान' में अमिताभ बच्चन के साथ, 'शेरदिल' में धर्मेंद्र के साथ, 'हमशक्ल' में विनोद खन्ना के साथ और 'तमाचा' में रजनीकांत के साथ भी यही भूमिका की है.

पहले उसका परिचय सुप्रसिद्ध पार्श्वगायिका सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन कहकर दिया जाता था. फिर उसे 'लव स्टोरी' की हीरोइन कहकर इंट्रोड्यूस कराया जाने लगा. बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो विजयिता पंडित को राजेंद्र कुमार की भावी कुलवधू माना जाने लगा. और जब उनके बेटे गौरव, सुनील दत्त के दामाद हो गए तब उसका नाम हो गया 'बेचारी विजयिता!'

विजयिता: भाग्य भरोसे

हालांकि विजयिता ने 'तू नहीं और सही' की तर्ज में मलकान परिवार की मालकिन बनकर राजेंद्र कुमार को जता दिया था कि हम किसी से कम नहीं. लेकिन लगता है कि सुखी वैवाहिक जीवन उनकी किस्मत में भी नहीं. पहले वे परिवार से अलग हुईं और अब खबर है कि कोर्ट में तलाक के कागजात दाखिल किए जा चुके हैं.

•••••••••••••

'रामा ओ रामा' में नए-नए आसिफ शेख पर 'किस' के मामले में हद दर्जे तक मेहरबान किमी काटकर ने दो बार के शादीशुदा राज बब्बर को ऐसी करारी मात दी है कि राज, पानी (दंत मंजन के लिए?) भी न मांग सके.

'अंधेरगर्दी' की शूटिंग पर राज बब्बर ने किमी के साथ रोमांटिक सीन तो किए लेकिन जब मामला होंठों पर होंठ रखने का आया तो वे अड़ गए.

इस इनकार का राज क्या था. किसी ने कहा, "वे किसिंग सीन की पब्लिसिटी से डरते हैं. उन्हें पालिटिक्स में जो जाना है." लेकिन जब किमी से पूछा गया कि राज बब्बर ने क्यों इनकार कर दिया?" तो किमी का कहना था, "राज नहीं चाहते होंगे कि मैं वह राज खोल दूं."

क्या है वह राज?—"उनकी सांस में बदबू है."

किमी: राज रहने दो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आलीशान, आकर्षक, फ़ैशनेबल... बेहतरीन विमल सूटिंग की कहानी...रवि शास्त्री की जुबानी.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्दियों के लिए ☐ विमलकी ☐ पेशकश

विजेताओं की शान

VIMAL

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एअर इंडिया

महाराजा से छेड़खानी

राजन जेतली की नई प्रबंधन शैली से कर्मचारियों में नाराजगी

वे जर्जर एअर इंडिया को एक आधुनिक, समर्थ निगम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जादूगर की तरह. लेकिन उनके सहयोगी उनकी तुलना अयातुल्ला से करते हैं. उनका कहना है कि वे बदलाव की बनी-बनाई घुट्टी पुराने कर्मचारियों के हलक के नीचे जबरदस्ती उतारना चाहते हैं.

एअर इंडिया के 38 वर्षीय प्रबंध निदेशक राजन जेतली के बारे में सचाई इन सबके बीच कहीं है. जेतली ने आनन-फानन में बदलं देने की अपनी छवि के अनुरूप जर्जर एअरलाइन को नई शक्ल देने के लिए उच्च स्तर के कर्मचारियों में भारी फेरबदल किए, जिससे अंशकालिक अध्यक्ष, पिछले निदेशक मंडल के सदस्य और संचालन, इंजीनियरिंग तथा वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारी उनसे नाखुश हो गए. कड़े और रातोरात परिवर्तन चाहने वाले उपायों से पायलट, इंजीनियर और विदेश स्थित केंद्रों के प्रबंधक भी भड़क उठे. इसका नतीजा यह हुआ कि कई उड़ानों में बाधा पड़ी और देर हुई. कई उड़ानें रद्द भी कर दी गईं. यात्रियों का विश्वास भी इतना हिल उठा कि एअरलाइन की सेवा सामान्य होने पर भी 18 नवंबर को बंबई से लंदन की एक सीधी उड़ान (एआई 129) में सिर्फ एक यात्री गया. इसके पहले लंदन की एक उड़ान में सिर्फ 9 यात्री गए थे.

सात हफ्ते तक चले आंदोलन से एअर इंडिया को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना मुश्किल है. इस आंदोलन के कारण 100 उड़ानें रद्द कर दी गईं और कम-से-कम 250 उड़ानों में 6 घंटे तक की देर हुई. इससे पूरी दुनिया में विभिन्न हवाई अड्डों पर खड़े लगभग 8,000 यात्री अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सके. जेनेवा से एअर इंडिया का संपर्क तीन हफ्ते कटा रहा जबकि सिडनी के लिए एअर इंडिया के किसी विमान ने दो हफ्ते तक उड़ान नहीं भरी.

हालांकि प्रबधन और ग्राउंड इंजीनियरों तथा पायलटों के बीच पिछले पखवाड़े किसी तरह से समझौता हो गया लेकिन निदेशक मंडल में एक नया संकट पैदा हो गया. प्रबंध निदेशक राजन जेतली की प्रबंधन शैली से नाखुश एअर इंडिया के अंशकालिक अध्यक्ष रतन टाटा ने अपना इस्तीफा देने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा. टाटा ने पिछले साल राजीव गांधी से दो बार शिकायत की थी कि एअर इंडिया को मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है. इधर प्रधानमंत्री पर एअर इंडिया के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उधर योजना आयोग में एअर इंडिया के निजीकरण की सिफारिश वाली एक टिप्पणी पहुंची. इंदिरा गांधी के पूर्व प्रमुख सचिव पी.एन. हक्सर द्वारा तैयार की गई इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री कार्यालय ने योजना आयोग के पास भेजा था. योजना आयोग ने यह जानकर इस सिफारिश को रद्द कर दिया कि अगर सरकार ने एअरलाइन को बेचने का फैसला किया तो टाटा घराना उसे खरीद सकता है.

क्या हाल का आंदोलन एक और सामान्य किस्म का संकट था या वह किसी गंभीर बीमारी, निगम की दोषपूर्ण संस्कृति का संकेत है. इस संस्कृति के बारे में जेतली का कहना है कि यदि एअरलाइन को इस जबरदस्त होड़बाजी वाले उद्योग में टिके रहना है तो निगम की खामियों को दूर करना ही होगा. लेकिन इस पर लोगों की एक राय नहीं है. एअर इंडिया के पुराने लोगों का कहना है कि जेतली ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो बहुत जरूरी थे.

जेतली ने मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में अपने 18 महीने के कार्यकाल में एअरलाइन पर से प्रमुख मजदूर संघों की पकड़ खत्म करने की कोशिश की. पिछले साल उन्होंने कैबिन चालक दल संघ की हड़ताल तोड़ दी और उसके अध्यक्ष मोहनबीर सिंह और कुछ दूसरे सदस्यों को निलंबित कर दिया. कुछ महीने पहले उन्होंने बोइंग 747 के कमांडरों को नौ घंटे के बदले साढ़े दस घंटे की उड़ानें भरने के आदेश देकर इंडियन पायलट्स गिल्ड को भी ललकारा. उन्होंने लगभग

एअर इंडियाः बुरा हाल

राजन गोडवाल

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टाटा कहते हैं, "सिर्फ डंडे के जोर से काम नहीं होता. उसमें अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, कर्मचारियों को अपने साथ लेकर चलना होता है"

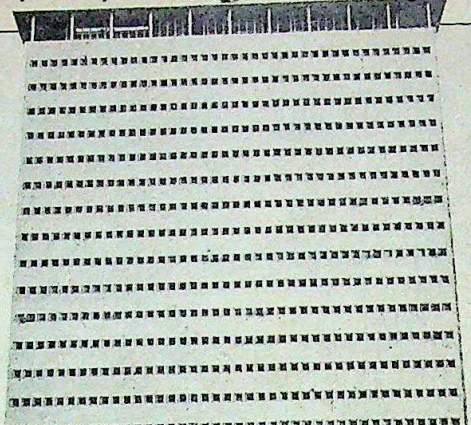

जेतली कहते हैं, "कोई भी बड़ा निगम कर्मचारियों और उनकी कार्यशैली में भारी परिवर्तन किए बिना मुनाफा नहीं कमा पाया है"

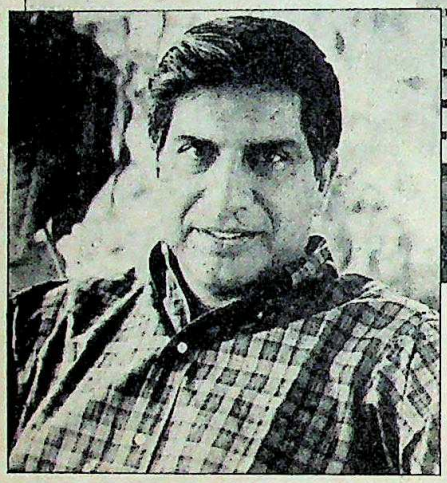

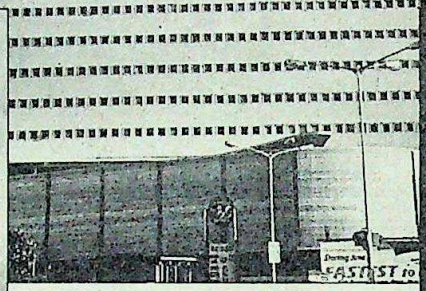

1300 प्रबंधकों के प्रथम श्रेणी के विशेषाधिकारों को रद्द कर दिया और विदेश से सभी केंद्रों के प्रबंधकों को मिलने वाली ड्राइवर की सुविधा खत्म कर दी.

ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एअर इंडिया की प्रथम और क्लब श्रेणी की सुविधा की गुणवत्ता और विशिष्टता में सुधार लाने के जेतली के घोषित मकसद से सहमत न हों. साथ ही कर्मचारियों को इन श्रेणियों में यात्रा करने की मनाही से भी शायद ही कोई असहमत हो. भारत से न्यूयॉर्क तक की उड़ान के लिए 60,000 रु. देकर प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री एअर इंडिया से बार-बार शिकायत करते रहे हैं कि इकॉनामी वर्ग के यात्रियों की यात्रा का स्तर बढ़ाया जा रहा है. वे सिर्फ 14,000 रु. किराया देते हैं और यात्रा करते हैं प्रथम श्रेणी में. इस बात पर भी सहमति है कि जब एअरलाइन घाटे में चल रही हो तो कर्मचारियों के विशेष भत्ते में कटौती की जरूरत है.

टाटा का कहना है, "यह अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती." एअर इंडिया के अधिकारियों की पत्नियां प्रथम श्रेणी को बैठकखाना समझ लेती हैं जहां वे सिलाई मशीन रेफ्रिजरेटर और विदेश में नियुक्तियों के बारे में जोर-जोर से चर्चा करती हैं. और उनके बच्चे शोर करते हुए ऊपर-नीचे दौड़ते रहते हैं. टाटा कहते हैं, "मैंने यह सब खुद देखा है जिससे कोफ्त होती है."

जेतली की एक समस्या है एअर इंडिया के महाराजा के प्रति तिरस्कार की भावना. एअर इंडिया का महाराजा उम्मीदें तो बहुत जगाता है लेकिन एअरलाइन उसे पूरा नहीं कर सकती. जेतली उसकी छवि को बदलने का पक्का इरादा कर चुके हैं. अमेरिका स्थित एक सलाहकार विमानों के लिए नई लिवरी, भीतरी साज-सज्जा, नया लोगो, लेटर हेड और विमान परिचारिकाओं तथा पायलटों के लिए नई वर्दी की डिजाइन तैयार कर रहे हैं.

जेतली ने सुधार के जो कड़े कदम उठाए हैं, उन्हें देख पर्यवेक्षक मानने लगे हैं कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों से प्रबंध निदेशक के अच्छे संबंध हैं और उन्हें एअर इंडिया को दुरुस्त करने के लिए पूरे अधिकार मिले हुए हैं. जेतली ने नागरिक उड्डयनमंत्री जगदीश टाइटलर द्वारा मनोनीत वाणिज्य निदेशक मलिक को हटाकर भी अपनी ताकत दिखा दी. उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग को भी दो भागों में बांट दिया. इसके अलावा इंजीनियरिंग और वित्त विभाग के निदेशकों को भी बदल दिया गया. मलिक और उप प्रबंध निदेशक सी.एल. शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया. निदेशक मंडल के उन सदस्यों को भी नए मंडल में नहीं लिया गया जिन्होंने जेतली का जीना दुश्वार कर दिया था. इन सब का मतलब साफ था—एअर इंडिया के अध्यक्ष रतन टाटा के लिए भी.

आखिरकार टाटा ने कई साल तक कुछ चुपचाप सहने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और जेतली के साथ अपने तीखे मतभेदों को उजागर कर दिया. टाटा ने 'इंडिया टुडे' से कहा कि एअर इंडिया के कर्मचारियों का "मनोबल बहुत गिर गया है. उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है." ग्राउंड इंजीनियरों और पायलटों ने उनसे शिकायत की कि एअरलाइन को "बातचीत की बजाए स्वेच्छाचारी कार्रवाइयों और प्रशासनिक आदेशों के जरिये चलाया जा रहा है." टाटा मानना है कि उनकी शिकायत पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि हर कर्मचारी को अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए. एअर इंडिया प्रबंधकों के प्रथम श्रेणी के विशेषाधिकारों को खत्म करने के मामले में भी वे जेतली से सहमत नहीं हैं. "आप के के उन विशेषाधिकारों को स्वेच्छाचारी नहीं कह सकते जिनका वे वर्षों से सही गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके लिए विचार-विमर्श की जरूरत होती है. सिर्फ के जोर से काम नहीं होता. उसमें अभि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

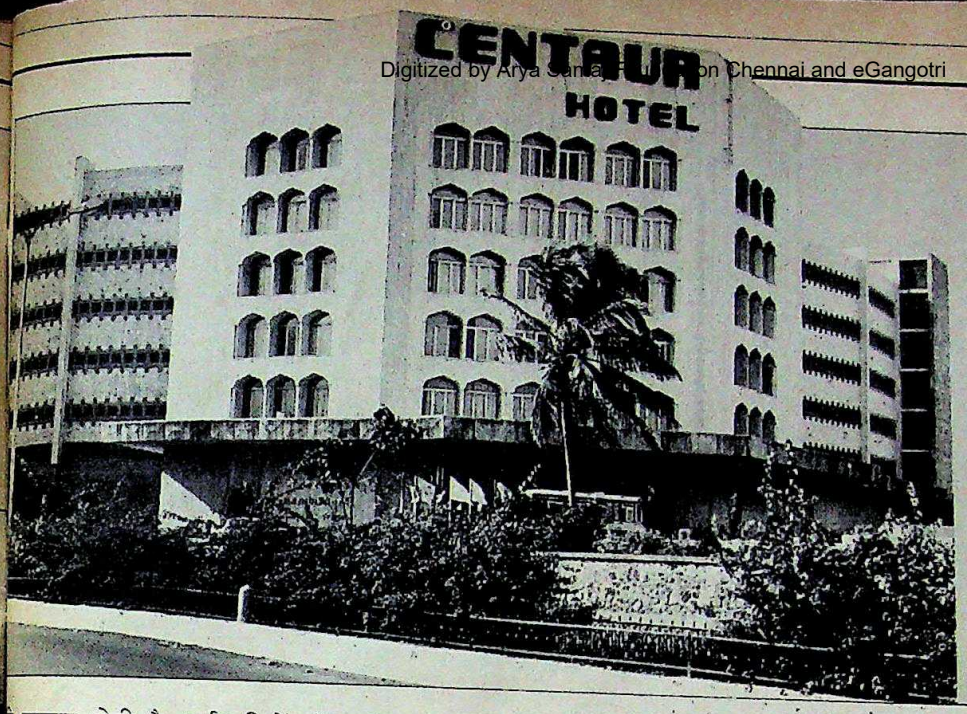

जेतली कहते हैं कि होटल कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया को बेचने का फैसला अभी तक नहीं हुआ है. वे खुद चाहते हैं कि दिल्ली और बंबई के हवाई अड्डों पर स्थित दोनों होटल एअर इंडिया के पास ही रहें

ी जरूरत होती है, कर्मचारियों को अपने ाथ लेकर चलना होता है.''

मिसाल के तौर पर, पायलट संचालन निदेशक डी.एस. माथुर के उस शासनिक आदेश' से चिंतित हो उठे जिसमें इंग-747 के पायलटों के उड़ान का समय ढ़ा दिया गया था. 1971 के प्रबंधन और ड्यन पायलट्स गिल्ड के बीच हुए समझौते उड़ान की अवधि की सीमा 9 घंटे रखी गई लेकिन नए आदेश में कार्य के घंटे बढ़ा ए गए ताकि एअर इंडिया के विमान दुबई बिना उतरे सीधे लंदन जा सकें. पहले के झौते में जब उड़ान के लिए अधिकतम नौ रखे गए थे तो एअर इंडिया को भारत-'इंडिया टुडे' न मार्ग पर विमान उतारने के लिए कर्मचारियों बूर होना पड़ता था. यानी साढ़े तीन घंटे है. उन्हें ह उड़ान के बाद पायलट और चालक दल ग्राउंड 20 सदस्य दुबई में रात में विश्राम करते से शिकायत और विमान को नया चालक दल लंदन ले त की. बनि ना था. वापसी में भी ऐसा ही होता था. र प्रशास पायलटों ने हाईकोर्ट में इस आदेश को ा रहा है. ौती दी. कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर यत पर वि लेकिन एअर इंडिया के प्रबंधन ने लंदन र कर्मचारी की अविराम उड़ान भरने वाले हर त सुनी ज लट को 500 डॉलर का अतिरिक्त भत्ता प्रथम श्रेणी शुरू कर दिया.

ने के मामले बोइंग-747 के पायलटों को मिलने वाले हैं, ''आप लाभ से उनके और एअरबस के कमांडरों च्छाचारी बीच दरार पड़ गई. एअरबस के कमांडरों वर्षों से सह मानना था कि उनके साथ भेदभाव किया रहे हैं. इस 22 सितंबर के आदेश के बाद, जिसमें ती है. सिर्फ की प्रथम श्रेणी की यात्रा सुविधा खत्म कर समें अभि गई थी, उन्होंने बीमारी की छुट्टी लेनी शुरू कर दी.

लगभग 20 वरिष्ठ पायलटों ने यह कहते हुए चेक-पायलट के रूप काम करने से इनकार कर दिया कि इस तरह के ज़ोखिम भरे काम के लिए 300 रु. का भत्ता अपर्याप्त है. इससे एअरलाइन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रुक गया. पायलटों की मौजूदा कमी की वजह भी यही है. इस आखिरी कदम से एअरलाइन को सबसे अधिक धक्का पहुंचा. संचालन निदेशक डी.एस. माथुर ने माना, ''समस्त प्रशिक्षण का काम रुक गया है.''

जेतली एअर इंडिया के विदेश स्थित केंद्रों के प्रबंधकों के ड्राइवरों को हटाने के अपने फैसले का बचाव करते हैं. उन्होंने 'इंडिया टुडे' से कहा, ''न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर प्रतिमाह 1638 डॉलर (लगभग 23,000 रु.) के वेतन पर ड्राइवर रखने की क्या तुक है या फिर तोक्यो में ही ड्राइवर रखने की क्या जरूरत है जहां कि हर माह 26,300 रु. वेतन देने के अलावा सात माह के वेतन के बराबर बोनस भी देना पड़ता है?''

अतिरिक्त खर्चों में कटौती के लिए जेतली ने लंदन कार्यालय को आदेश दिया कि वहां नियुक्त लगभग 80 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाए और हीथ्रो में सभी एअर इंडिया उड़ानों की ज़मीनी देखभाल का काम ब्रिटिश एअरवेज को सौंप दिया जाए. इसके बाद न्यूयॉर्क का नंबर है जहां एअर इंडिया ने रोज़ की एक उड़ान के लिए 250 कर्मचारी रखे हुए हैं.

एअर इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि जेतली इस साल मुनाफा दिखाने के इतने इच्छुक हैं कि वे इसके लिए एअर इंडिया की सहायक कंपनी होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई) और उसकी दूसरी संपत्ति तक को बेचने का इरादा बना रहे हैं. इस संपत्ति में हांगकांग स्थित कंपनी का एक फ्लैट और दो पुराने बोइंग 747 शामिल हैं. जेतली इसका खंडन करते हैं. उनका कहना है कि राष्ट्रीय पर्यटन समिति ने एचसीआई को भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) में मिलाने की सिफारिश की है. लिहाजा मंत्रालय एचसीआई के भाग्य पर अभी भी विचार-विमर्श कर रहा है. जेतली खुद चाहते हैं कि दिल्ली और बंबई के हवाई अड्डों पर स्थित दोनों होटल एअर इंडिया के पास ही रहें.

एचसीआई के घाटा देने वाले हिस्से को अगर बेचा गया तो वह जेतली की कार्यशैली के ही अनुरूप होगा. जब वे भारतीय पर्यटन विकास निगम में थे तो उन्होंने दिल्ली के अकबर होटल को निगम से अलग कर दिया.

जहां तक जेतली का सवाल है, मुद्दा एअरलाइन के कर्मचारियों की शिकायत से कहीं ज्यादा बड़ा है. वे कहते हैं, ''कोई भी बड़ा निगम कर्मचारियों और उनकी कार्यशैली में भारी परिवर्तन किए बिना मुनाफा नहीं कमा पाया है. मिसाल के तौर पर क्रिसलर और ब्रिटिश एअरवेज को लिया जा सकता है.'' जर्जर एअर इंडिया को चुस्त-दुरुस्त बनाने की जरूरत निश्चित ही है. लेकिन जेतली जबरदस्ती सुधार थोप रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा दरकिनार हो गया है. जेतली जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वे एअर इंडिया के हजारों कर्मचारियों के लिए मुद्दा नही हैं. मुद्दा यह भी नहीं है कि वे निगम की संस्कृति बदलना चाहते हैं. बल्कि उनके लिए जेतली ही मुद्दा हैं. —**रमिंदर सिंह, बंबई में**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय वायुसेना

हवाई हादसों को अभिशप्त

कारण; घटिया विमान, कमजोर प्रशिक्षण और साधनों की कमी

कुछ समय से प्रतिरक्षा संबंधी योजनाकार भारतीय वायुसेना के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की रफ्तार से चिंतित हैं. लेकिन पिछले पखवाड़े 10 दिनों के भीतर पांच लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी परेशानी की कोई सीमा ही नहीं रही. इससे वायुसेना के उच्चाधिकारी सात लड़ाकू विमान दस्तों की कड़ी जांच के आदेश देने को मजबूर हुए. छानबीन करती रिपोर्ट:

एक हफ्ते से अधिक समय तक दिल्ली-वासी नीचे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों के शोर से अभ्यस्त रहे. हर रोज सुबह 9.30 बजे वायुसेना के स्क्वाड्रन 17 के मिग-25 एम (त्रिशूल) विमान राजधानी के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों के ऊपर 'बी' की आकृति बनाते हुए निकलते. ये विमान उस अलंकरण समारोह के लिए अभ्यास कर रहे थे जिसमें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन भाग लेने वाले थे. आयोजन के दिन तक सारा कुछ ठीकठाक चल रहा था. उस दिन अचानक एक मिग झोंपड़पट्टी पर आ गिरा और उसने चार लोगों की जान ले ली. विमान चालक आर. मलहोत्रा कुशलपूर्वक बच निकलने में कामयाब रहे.

लेकिन राजधानी में हुई इस दुर्घटना से विमानों को इतने नीचे उड़ाने के सवाल पर बवंडर उठ खड़ा हुआ. तत्काल वायुसेना के विमानों की क्वालिटी, रखरखाव और चलाने के बारे में भी सवाल उठाए गए. उसी समय हुई दूसरी दुर्घटनाओं की खबरें अखबारों तक नहीं पहुंच पाईं, वरना और हंगामा खड़ा होता. दिल्ली वाली दुर्घटना के 48 घंटों के अंदर ही तीन और मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे. सौभाग्य से ये दुर्घटनाएं निर्जन इलाकों में हुईं लेकिन इन्होंने उस हफ्ते को वायुसेना के शांतिकाल के इतिहास का बेहद स्याह हफ्ता जरूर बना दिया.

हफ्ते भर बाद एक और मिग जामनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. तब जाकर वायुसेना के अधिकारी चेते. तुरंत वायु भवन ने मिग की 'एम' या 'एमएफ' किस्मों को उड़ाने वाले सात लड़ाकू स्क्वाड्रनों को उड़ान न भरने देने का फैसला किया. इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (हाल) ने किया था. 1985 में भी मिग स्क्वाड्रनों को इसी प्रकार के आदेश दिए गए थे. हद तो यह कि यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब वायुसेना को अपने ऊपर लगे अधिक दुर्घटना दर के आरोप का सामना करना पड़ रहा है. भारत में प्रति 10 हजार घंटे की उड़ान पर 1.4 दुर्घटनाएं होती हैं जबकि अमेरिकी वायुसेना की दर प्रति एक लाख घंटे की उड़ान पर .65 दुर्घटनाएं हैं. वैसे 1987 का साल भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बुरा साबित हुआ था जब भारत में 53 बड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं.

लेकिन पिछले पखवाड़े की दुर्घटनाओं का शोर इसलिए अधिक मचा क्योंकि सभी दुर्घटनाग्रस्त विमान एक ही किस्म के थे. गड़बड़ी की मुख्य वजह सभी लोग इंजन की खराबी ही मान रहे थे. बिना किसी चेतावनी के पायलटों ने अपने इंजन को फेल हुआ या लपटों से घिरा पाया और उनके सामने पैराशूट के सहारे छलांग लगा देने के अलावा कोई रास्ता न था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सौभाग्य से हर बार पायलट बच गए. लेकिन जिन विमानों का इंजन पूरी तरह दुरुस्त न हो उन्हें कौन उड़ाना चाहेगा?"

वायु भवन के उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार रूस के कच्चे माल से देश में ही बनाए जा रहे इंजनों में कोई गड़बड़ी है. लेकिन यह 1985 वाली समस्या से अलग है. तब की दुर्घटनाएं विमान के ऊपर लगने वाले उष्मारोधी कवच में गड़बड़ी के कारण हुई थीं. इससे विमान के पिछले हिस्से में आग लग जाती थी. एक और अनुमान यह है कि इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ने वाली धुरी में गड़बड़ी है. पहले भी वायुसेना इस धुरी को जोड़ने के लिए लगे दो बोल्टों के बारे में शिकायतें कर चुकी है.

मौजूदा संकट ने 'हाल' और उसके सबसे

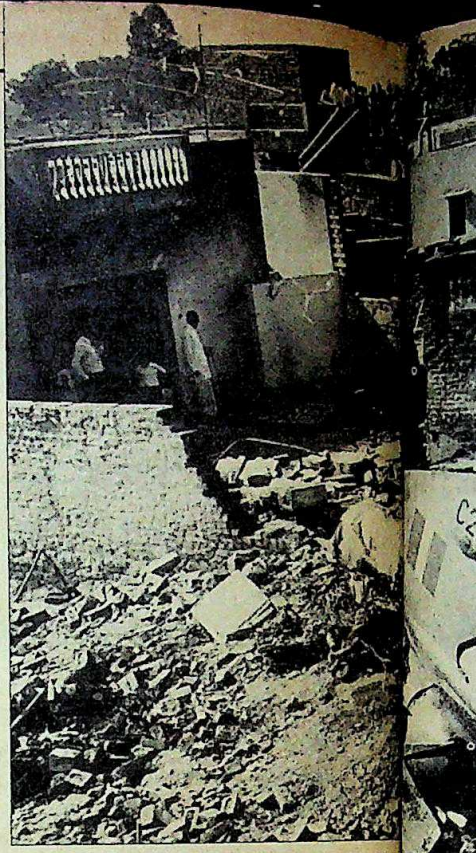

बड़े ग्राहक वायुसेना के बीच एक बार फिर विवाद पैदा कर दिया है. वायुसेना ने 'हाल' के क्वालिटी कंट्रोल के खिलाफ प्रतिरक्षा मंत्रालय में फिर शिकायत की तो देश के विमान निर्माण में एकाधिकार रखने वाली यह कंपनी तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गई. 'हाल' के योजना निदेशक एअर वाइस मार्शल यू. खुशलोनी कहते हैं, "हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दोषी ठहराना सर्वथा अनुचित है. हमारा क्वालिटी कंट्रोल एकदम बढ़िया है. सभी जानते हैं कि हमारी करीब 50 फीसदी दुर्घटनाएं पक्षियों के टकराने से होती हैं."

वायुसेना के अधिकारी बताते हैं कि 'हाल' द्वारा तैयार दूसरी किस्म के विमानों में भी मुश्किलें पैदा होती रही हैं. एक एयर मार्शल कहते हैं, "जगुआर से हमें अनेक शिकायतें रहीं. लेकिन इसमें दो इंजन होने से यह मिग की तुलना में अधिक भरोसेमंद है. करीब हर साल मार्च में विमानों की डिलिवरी को लेकर वायुसेना और 'हाल' के अधिकारियों के बीच चख-चख होती रहती है.

'हाल' के लोग निजी बातचीत में वायुसेना पर दोष लगाने से बाज नहीं आते. एक अधिकारी ने कहा, "गड़बड़ होने पर हर बार हमें दोषी ठहराने के बजाय बेहतर यही होगा कि वायुसेना अपने रखरखाव के तरीकों और पायलटों के प्रशिक्षण के स्तर पर पुनर्विचार करें." 'हाल' के अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना को न सिर्फ उनके यहां की बल्कि अनेक दूसरी मशीनों से भी शिकायतें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

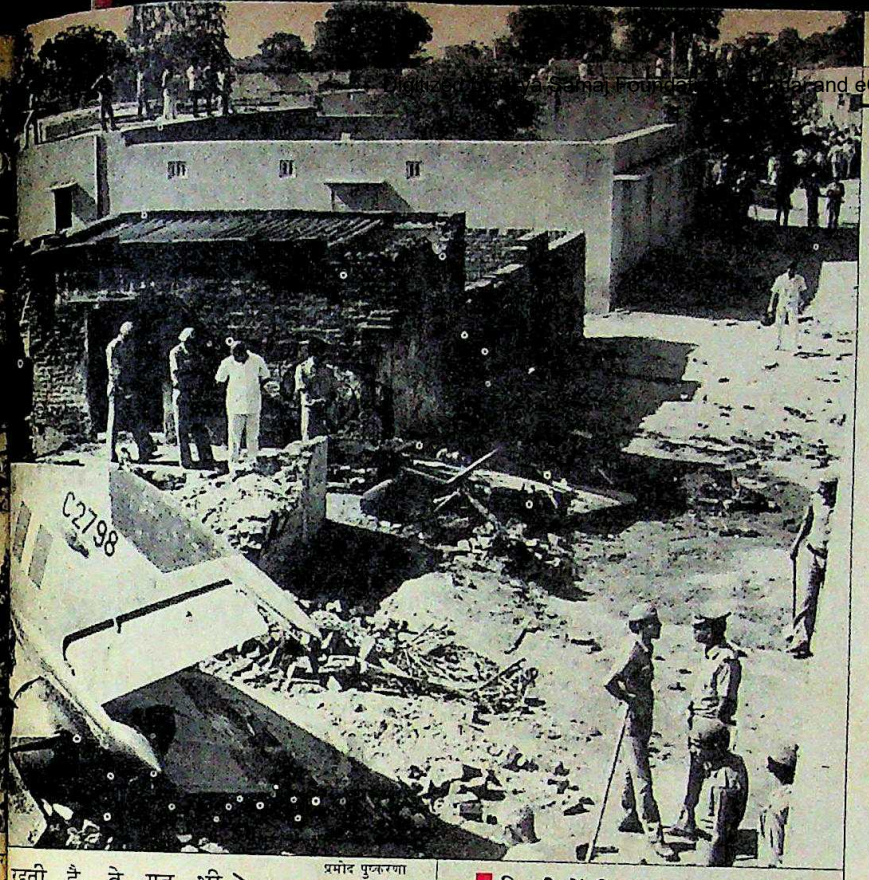

प्रमोद पुष्करणा

■ दिल्ली में बिखरा मलबा; और (नीचे) मिग 21: दुर्घटना का चक्कर

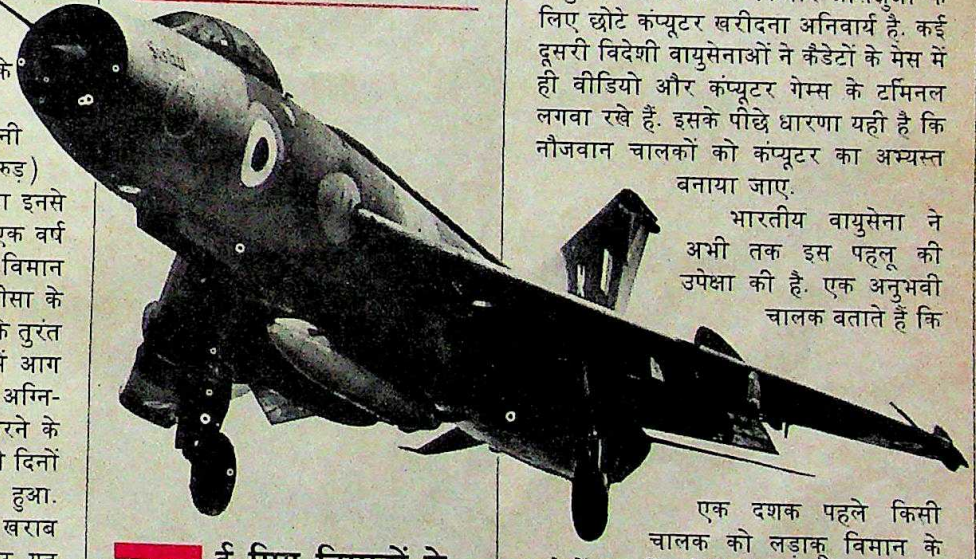

कई मिग विमानों के हाल में दुर्घटनाग्रस्त होने से वायुसेना के विमानों की क्वालिटी, रखरखाव और उनसे काम लेने के तौर-तरीकों पर सवाल उठे हैं

रहती है. वे यह भी बताते हैं कि दो अति-आधुनिक मिराज-2000 विमान भी हाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, पहला हरियाणा में सिरसा के पास और दूसरा ग्वालियर के पास.

इसी प्रकार, आवाज से तिगुनी रफ्तार से चलने वाले मिग-25 (गरुड़) भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और 'हाल' का इनसे कोई लेना-देना नहीं था. फिर, इसी एक वर्ष में सोवियत संघ में बने दो मालवाहक विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुए. अक्तूबर में ओडीसा के जरबतिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एएन-12 विमान के इंजन में आग लग गई थी और विमान पर मौजूद अग्नि-शमन उपकरणों का पूरा इस्तेमाल करने के बावजूद वह ध्वस्त हो गया था. कुछ ही दिनों बाद एक एएन-32 भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ. विमानन अनुसंधान केंद्र ने इसके लिए खराब मौसम को जिम्मेवार बताया था. पर यह विमान बहुत आधुनिक है और इसमें बहुरंगी मौसम राडार लगा हुआ है. ऐसे में मौसम की गड़बड़ी से दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी.

वायुसेना प्रमुख एस.के. मेहरा कहते हैं कि वायुसेना दुर्घटनाएं घटाने के बारे में सचेष्ठ हैं. लेकिन अधिकारियों का कहना है कि भारतीय वायुसेना को जिन रणनीतिक और मौसम संबंधी मुश्किलों में काम करना होता उससे यहां पश्चिमी देशों की तुलना अधिक दुर्घटनाएं होगी ही. एक एअर मार्शल कहते हैं, "हमारी वायुसेना इस कदर सक्रिय है कि हमें एक दिन की सूचना पर भी लड़ाई में कूदना पड़ सकता है. इसलिए हमें अक्सर नीची और जोखिम भरी उड़ानें भरनी होती हैं." विशेषज्ञ बताते हैं कि एक औसत भारतीय विमान चालक अमेरिकी चालकों की तुलना में दुगनी और चीनी चालकों की तुलना में तिगुनी उड़ानें भरते हैं. इसी प्रकार, नीची उड़ान भरने के कारण भारत में विमानों के पक्षियों से टकराने की घटनाएं भी अधिक होती हैं. लेकिन वे मानते हैं कि अभी यह दर कम करने की गुजांइश है. चालकों के प्रशिक्षण को आधुनिक बनाकर इस दर को काफी कम किया जा सकता है.

और यह मुद्दा आज सचमुच वायुसेना की कमजोर नब्ज है. देश ने लड़ाकू और माल-वाहक विमानों के आधुनिकीकरण में भले ही बहुत तरक्की कर ली हो लेकिन उन्हें चलाने के प्रशिक्षण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया. इसी चीज से वायुसेना की कुल ताकत प्रदर्शित होती है. दुनिया की दूसरी वायु-सेनाओं ने जंहां अपने यहां प्रशिक्षण में तेजी से सुधार किया है, वहीं भारत में ऐसा नहीं हो पाया है. कोलोरैडो स्प्रिंग्स स्थित अमेरिकी वायुसेना अकादमी में किशोर प्रशिक्षुओं के लिए छोटे कंप्यूटर खरीदना अनिवार्य है. कई दूसरी विदेशी वायुसेनाओं ने कैडेटों के मेस में ही वीडियो और कंप्यूटर गेम्स के टर्मिनल लगवा रखे हैं. इसके पीछे धारणा यही है कि नौजवान चालकों को कंप्यूटर का अभ्यस्त बनाया जाए.

भारतीय वायुसेना ने अभी तक इस पहलू की उपेक्षा की है. एक अनुभवी चालक बताते हैं कि एक दशक पहले किसी चालक को लड़ाकू विमान के बारे में कुछ मिनटों में ही पूरा खुलासा किया जा सकता था लेकिन "आज चालकों को अपना कंप्यूटर सेट करने और सारे आंकड़े भरने वगैरह के कारण इस प्रक्रिया में कम-से-कम डेढ़ घंटा लग जाता है." भारतीय वायुसेना ने कामचलाऊ तौर पर अपनी टेट्रा (टेक्निकल टाइप ट्रेनिंग) और एमसीएफ (मेंटेनेंस कंवर्शन फ्लाइट) योजनाओं के तहत विशेष स्कूल खोले हैं. इनमें नए विमानों को उड़ाने और उनमें अभ्यस्त होने के लिए चालकों को 22 से लेकर 24 हफ्तों का एक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है.

लेकिन भारतीय वायुसेना की असली मुश्किल आधुनिक प्रशिक्षकों की कमी होना है. दुनिया की इस पांचवीं सबसे बड़ी वायुसेना के पास ऐसे आधुनिक प्रशिक्षक नहीं हैं जो चालकों को मिराज और मिग-29 जैसे विमानों की उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले उन्हें भली भांति प्रशिक्षित कर सकें.

इसलिए जहां लड़ाकू स्क्वाड्रनों में बड़ी तेजी से कैनबरा की जगह जगुआर और हंटर की जगह मिराज आ गए हैं, वहीं चालकों को प्रशिक्षण अभी भी बाबा आदम के जमाने वाले 'किरण' और पुराने 'पोलिश इस्करा' विमानों पर ही मिलता है. पिछले साल भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए में ब्रिटिश हॉक या फ्रांसीसी अल्फाजेट विमान खरीदने की बात करीब-करीब पक्की कर ली थी लेकिन सूखे के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी.

इसके बाद कई कम खर्चीले तरीकों पर भी विचार किया गया. एक समय तो सोवियत संघ से बहुत कम कीमत पर बड़ी संख्या में मिग-21 यू ट्रेनर मंगाने पर विचार होता रहा था. लेकिन साठ के दशक के विमान से 21वीं सदी के विमान चालक को प्रशिक्षित करने का कोई मतलब नही था. और फिर, यह विमान प्रशिक्षण के मामले में कामचलाऊ ही है. इसमें प्रशिक्षु की सीट आगे है. प्रशिक्षक उसके पीछे बैठता है और उसके पास नियंत्रण वाले पूरे उपकरण भी नहीं होते. साथ ही उसकी सीट पायलट से काफी नीची होती है. इसलिए वह सामान्य रूप से यह नहीं देख पाता कि प्रशिक्षु क्या कर रहा है.

दूसरे प्रशिक्षण विमानों में प्रशिक्षक की सीट भी साथ ही होती है जिससे वह प्रशिक्षुओं को उनकी मुश्किलें सुलझाने में मदद करता है. अब इस बार अच्छी बरसात हो जाने के बाद नए प्रशिक्षण विमान खरीदने की बात फिर से उठी है. इसी वजह से अमेरिका की बड़ी जहाज कंपनी नॉर्थरोप ने पिछले दिनों अपने प्रशिक्षण विमान एफ-5 की खूबियां बताने के लिए एक टीम भारत भेजी थी. कंपनी ने अपने निर्माण की पूरी सुविधा भारत को देने की पेशकश की है और वह हॉक और अल्फाजेट की प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरी है.

किस विमान की खरीद होगी या खरीद होगी भी या नहीं—कहना मुश्किल है. बोफोर्स घोटाले के बाद रक्षा मंत्रालय रक्षा सौदों के बारे में बहुत चौकन्ना हो गया है.

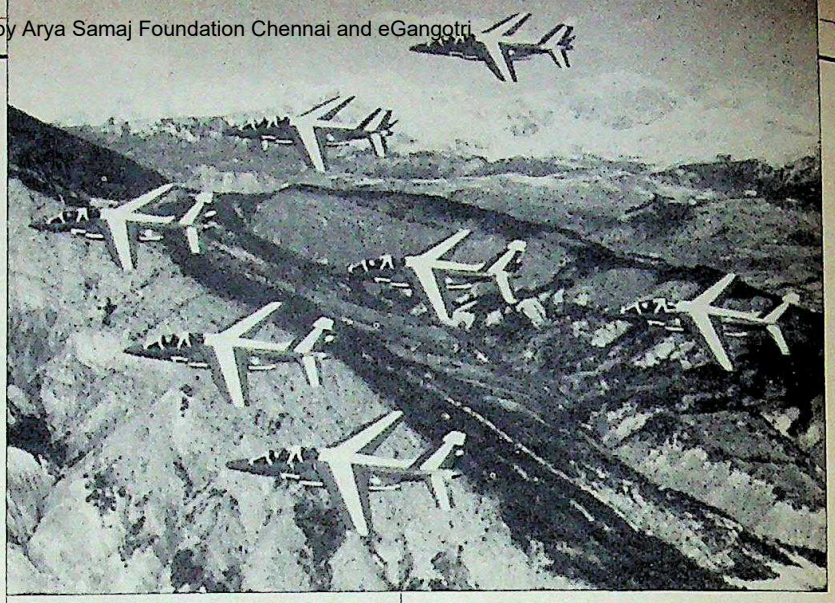

■ फ्रांसीसी अल्फाजेट; और (नीचे) एफ-5: तीखी होड़

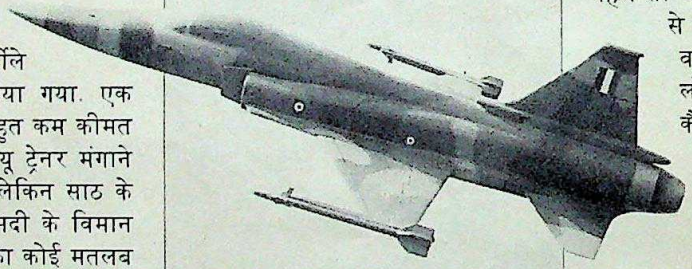

प्रशिक्षण विमान एफ-5 बनाने वाली कंपनी नॉर्थरोप ने इसके निर्माण की पूरी सुविधा भारत को सौंपने का प्रस्ताव रखा है

फिर, यह सौदा तो उससे दुगनी राशि का है लेकिन सौदा होने और विमानों की डिलीवरी मिलने में चूंकि साल भर का समय लग जाता है इसलिए इस पर जल्दी फैसला लेना जरूरी है. माना जाता है कि निवर्तमान वायुसेना प्रमुख डेनिस ए.ला' फांतेन ने सरकार से कहा था कि अगर प्रशिक्षण विमान खरीदने का फैसला जल्दी नहीं लिया गया तो चार-पांच वर्षों के भीतर वायुसेना की जरूरत के लायक प्रशिक्षित चालक तैयार कर पाना मुश्किल हो जाएगा.

विडंबना यह है कि वायुसेना के कई स्क्वाड्रनों में विमानों की संख्या चालकों से अधिक हो गई है. एक पुराने चालक का कहना है, "पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. पहले तो चालकों की संख्या हमेशा विमानों से ज्यादा हुआ करती थी." इसकी वजह प्रशिक्षण स्कूलों से कम लोगों का निकलना और युवा कैडेटों द्वारा इस काम में रुचि न लेना है. पहले तो लोग इस काम को बहुत ग्लैमर वाला माना करते थे.

चालकों की कमी के साथ ही करेले के नीम चढ़ने की भांति तकनीकी स्टॉफ की कमी भी होती जा रही है. हालत किस कदर खराब है, इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि वायुसेना अब अपने अवकाशप्राप्त लोगों को दोबारा नौकरी में लेने की पेशकश कर रही है. उम्मीद की जाती है कि ऐसे प्रस्ताव उन अधिकारियों को भी दिए जाएंगे जिन्होंने प्रोन्नति के मामले में पीछे छोड़ दिए जाने से कुंठित होकर नौकरी से अपना इस्तीफा दे दिया था.

वायुसेना के योजनाकारों का कहना है कि चालकों की कमी का मामला बहुत गंभीर है. अभी शायद यह कमी दुर्घटनाओं का कारण न हो पर आगे यह भारी संकट पैदा करेगी. एक चालक कहते हैं, "चाहे प्रशिक्षण विमान खरीदना हो या वायुसेना की नौकरी को आकर्षक बनाने के लिए भारतीय वायुसेना में वेतन-भत्ता बढ़ाना, हमें फैसले जल्दी लेने होंगे."

लेकिन दुर्घटनाएं एकदम बंद तो नहीं होंगी. वे तो इस पेशे से जुड़ी ही हैं. बहरहाल, भारतीय वायुसेना जैसे विशाल संगठन को खराब उपकरणों से तो मीलों दूर रखना होगा.

—शेखर गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी.टी. उषा

नाकामी, लानतों का दुख

सिओल ओलंपिक के निराशापूर्ण प्रदर्शन के बाद कई आघात

आनन-फानन में सफलता के शिखर पर पहुंचकर नाकाम होना अपराध है. और इस साल सितंबर माह के एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सिओल में 24 वर्षीय पी.टी. उषा नाकाम रहीं.

लेकिन निराश मुल्क ने लानतें उन पर नहीं भेजी. कालीकट से 42 किमी दूर अपने गांव पाय्योली लौटकर उषा ने एथलेटिक्स में अपने भविष्य के बारे में फैसला कर लिया है. उन्होंने फिर समुद्र के उसी किनारे पर अभ्यास शुरू कर दिया है जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था. पर लगता है अब वे टूट चुकी हैं. वे कहती हैं, "मैं 1989 में नई दिल्ली में होने वाली एशियाई ट्रैक ऐंड फील्ड प्रतियोगिता के बाद अवकाश ले लूंगी. मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ स्वर्ण पदक पाकर मैं आलोचकों का मुंह बंद कर सकूंगी. 1990 में पेडचिंग में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है."

इस बयान के कई मतलब निकल सकते हैं— स्वर्ण पदक के मामले में भी, जिसके कारण उषा को भर्त्सना का शिकार होना पड़ा. मुख्य रूप से घायल एड़ी के कारण इस ओलंपिक में अपमानजनक स्थिति का सामना करने के बावजूद उषा 1990 में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दो या तीन स्वर्ण पदकों की एकमात्र दावेदार हैं.

फिलहाल उषा के सामने प्रमुख समस्या अपने 51 वर्षीय प्रशिक्षक ओ. माधवन नांबियार से व्यावसायिक नाता तोड़ने की है. इसके लिए उन पर लोगों और साथियों का खासा दबाव है. दूसरी बातों के अलावा नांबियार से उनके संबंधों की आलोचना करते हुए पाय्योली में दीवारों पर नारे भी लिखे गए. एक बार क्रुद्ध भीड़ ने तो नांबियार को लगभग अधमरा ही कर दिया था. प्रशिक्षक और लंबी कूद के खिलाड़ी रहे सुरेश बाबू ने ओलंपिक में उषा की नाकामी का सारा दोष नांबियार के सिर मढ़ते हुए प्रतिष्ठित साप्ताहिक 'कलाकौमुदी' में आवरण कथा भी लिखी. लेख में उन्होंने लिखा कि "उषा का भविष्य अभी भी सुनहरा है, बशर्ते उसे नांबियार से छुटकारा दिलाया जाए".

मगर उषा पर इसका कोई असर नहीं है. नांबियार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पूर्ण है. इस आरोप पर कि नांबियार उनका कैरियर चौपट कर रहे हैं, वे सुबकते हुए कहती हैं, "मुझे कोई भी अपने प्रशिक्षक से अलग नहीं कर सकता. उन्हीं की बदौलत आज मैं यहां पहुंची हूं." नांबियार ने उषा के घर पर कहा, "सिओल के बाद हर कोई मेरा सिर उतार लेना चाहता है. पर मुझे इसकी चिंता नहीं."

केरल में जोरदार चर्चा है कि स्तरीय प्रशिक्षण न देकर उषा के कैरियर को चौपट करने के अलावा नांबियार ने उनकी उपलब्धियों के माध्यम से पैसा भी बनाया है. इससे मामला और गहरा गया है. नांबियार इसका खंडन करते हैं, "उषा के कारण मुझे निश्चय ही कुछ शोहरत मिली है पर मैंने कभी उसकी वजह से पैसा नहीं कमाया है. हमारे बीच बाप-बेटी जैसा संबंध है."

इसके उलट, खेल हलकों में यह प्रबल धारणा है कि अगर उषा ने किसी विदेशी प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लिया होता तो नतीजे कहीं बेहतर होते. केरल खेल परिषद तो अब उषा के निजी प्रशिक्षक के पद से नांबियार का तबादला करने की कोशिश कर रही है.

बहरहाल, उषा अनजाने ही सुनील गावसकर और बिशन सिंह बेदी से भी उलझ गई हैं. हुआ यह कि उनके स्तंभ लेखों के दिल्ली स्थित छद्म लेखक ने दोनों पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों की बेमतलब आलोचना कर दी. उधर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने उषा को बाचाल बालिका करार दिया.

> "मैं 1989 की एशियाई ट्रैक ऐंड फील्ड स्पर्धा के बाद अवकाश ले लूंगी. 1990 के एशियाई खेलों में मैं हिस्सा नहीं लूंगी"

लेकिन इस महान धाविका का आखिर क्या होगा? क्या सिओल ने उनके कैरियर पर परदा डाल दिया? उनके कैरियर पर पानी फेरने के साथ-साथ पदक हासिल करने की भारतीय आकांक्षाओं पर कुठाराघात करती उनकी घायल एड़ी पर किसी का ध्यान नहीं गया. देश और विदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के बजाय उषा का इलाज कन्नानूर के होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल अजीज से कराया जा रहा है. पर उनके पिता अब उनकी शादी कराना चाहते हैं.

लेकिन दुर्लभ पदक जीत न पाने के लिए दुखी, अपनी घायल एड़ी से परेशान, नांबियार से अटूट संबंधों के चलते और खेल प्रबंधकों द्वारा समय से पहले ही खारिज कर दिए जाने की त्रासदियां झेलती उषा के लिए सफलता की सीढ़ियां खत्म हो गई लगती हैं.

—श्रीधर पिल्लै, पाय्योली में

नांबियार और उषा: अटूट वफादारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आमिर खां

कयामत की मासूमियत

नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हीरो के आगे कई चुनौतियां

आमिर खां के प्रति आकर्षण से मानो उम्र का गहरा रिश्ता है. 20 साल से कम उम्र के युवक-युवतियां तो उन पर फिदा हैं जबकि इससे अधिक उम्र वाले हैरत में हैं कि इस शख्स को लेकर इस कदर आहें क्यों भरी जा रही हैं. फिल्म 'कयामत से कयामत तक' रिलीज होने के बाद 23 साल के आमिर खां किशोरों के आदर्श बन गए हैं— उस पीढ़ी के आदर्श जिसके लिए अमिताभ बच्चन पिता की पीढ़ी के हैं.

कई नवयुवतियों के पास सचमुच 'कयामत...' की वीडियो कॉपियां हैं और उसे वे 50 से ज्यादा बार देख चुकी हैं. एक लड़की तो हर रात फिल्म के कुछ भाग देखती है और आमिर खां के दिखने पर हर बार एक अदद चुंबन उनकी ओर उछालती हुई 'सोना बाबा' बुदबुदा देती है. एक दूसरी लड़की ने अपने कमरे से रातोरात वाल्ट डिज्नी के पोस्टर उखाड़कर आमिर खां की आदमकद तस्वीरें टांग दी हैं. वह कहती है, "उसकी आंखों, उसके होंठों में गजब का आकर्षण है. वह निहायत मासूम बच्चे सरीखा है."

कुछ महीने पहले जब अफवाह उड़ी कि आमिर खां दिल्ली के एक होटल में ठहरे हैं तो ग्यारहवीं जमात की अनेक लड़कियां साड़ी पहने दिन भर उस होटल में मंडराती रहीं. फिल्म 'राख' में आमिर के निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य कहते हैं, "आमिर यह आभास देते लगते हैं कि वे महिलाओं के प्रति सौम्य हैं. वे इस कदर मासूम लगते हैं कि आप उन्हें घर ले जाकर अपनी मां से मिलवाना चाहेंगी."

आमिर को तरह-तरह के प्रशंसकों की ढेरों चिट्ठियां मिलती हैं— हर दिन करीब 250. इनमें हैदराबाद की एक स्कूली लड़की द्वारा खून से लिखी चिट्ठी से लेकर विलासपुर के संजय वर्मा द्वारा भेजी अखबारों की कतरनें तक शामिल हैं. संजय अपने शहर में हीरो ही बन गया है क्योंकि उसने 'कयामत...' 70 दिन में 65 बार देखी है. गोवा की एक स्कूली लड़की ने तो आमिर के चाचा और फिल्म निर्माता नासिर हुसैन तक को चिट्ठी लिख डाली, "मैं न तो ठीक से खा सकती हूं, न सो सकती हूं. ख्वाब में मैंने देखा कि आमिर मेरे लिए पैगाम लाए हैं. कुछ सूझता नहीं, मैं क्या करूं?"

'कयामत...' उन दो नौजवां दिलों की मुहब्बत की कहानी है जिनके परिवारों में आपसी रंजिश है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसमें परीकथाओं-सा आकर्षण है, एक आकस्मिकता है. पर 'देवदास' या 'प्यासा' सरीखी फिल्मों के मुकाबले यह उन्नीस पड़ती है. निर्देशक शेखर कपूर का मानना कि "हर 10 साल बाद दर्शक अपने बदल जाने का संकेत देते हैं. आमिर ने पूरी की पूरी नई पीढ़ी का काफिया ही बदल डाला है, वैसे ही जैसे कभी जीनत अमान ने बदला था."

एक तरह से 'कयामत...' ने हर ओर दीवानगी का आलम फैला दिया है. कई बच्चों ने तो इसके कुछ खास दृश्यों को सौ-सौ बार देखा है. बंबई में आमिर के 19 वर्षीया प्रशंसक गौरी पटेल कहती हैं, "उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हमारी तरह ही सामान्य दिखता है."

दरअसल आमिर है भी एक सामान्य-सा ही लड़का, जिसने बांबे-स्कॉटिश में तालीम पाई है, खाली समय टेनिस खेलता है और मोहल्ले की एक लड़की से इश्क किया है. उन्हें यह भी नहीं पता कि अपने प्रशंसकों से कैसे पेश आएं. आमिर कहते हैं, "मेरे प्रशंसक इस बात से परेश

आमिर खां; और (दाएं) 'कयामत से कयामत तक' का दृश्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है कि मुझसे क्या कहें और मैं इसे लेकर परेशान हूं कि उनसे क्या कहूं. 22 साल तक तो किसी ने मेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखा.''

आखिर आमिर खां की डुगडुगी क्यों पिटने लगी? ज़रा गौर से देखें तो फिल्म उद्योग में नौजवानों की भरमार है. एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्था, मोटर साइकिलों पर सवार, डिस्कोथे में नाचते-गाते धूम मचाते युवकों की भीड़ है. पर आमिर इस भीड़ से अलग दिखते हैं. उनके मुकाबले कोई भी सीधा-सादा, मासूम नहीं दिखता. भट्टाचार्य कहते हैं, दुनिया दिनं-ब-दिन दिखावटी और नीरस होती जा रही है. ऐसे में आमिर खां की आंखों में झांकने से शीतलता मिलती है. आमिर की कामयाबी अच्छाई की कामयाबी है.''

आमिर फिल्म में मुहब्बत का संदेश देने में भी कामयाब रहे हैं. कपूर कहते हैं, ''मुद्दतों बाद मुझे किसी फिल्म में सच्ची मुहब्बत दिखाई दी. वरना बाकी फिल्मों में नायक नायिका से ज्यादा खुद से ही मुहब्बत करता दिखाई देता है.'' निर्देशक अमित खन्ना कहते हैं, ''बाल सुलभ आकृति और उस पर कुछ कदर संजीदगी, यही आमिर की खूबी है.''

पर अमिताभ और राजेश खन्ना के युग की 30 वर्षीय पीढ़ी में यह बदलाव इतनी जल्दी नहीं होने वाला. आमिर को अभिनय में भी कमाल दिखाना होगा. उनकी अगली फिल्म 'राख' से ही देगी कि उनमें कितना दम है. 'राख' तड़क-भड़क से भरपूर एक अति-यथार्थवादी फिल्म है. उस हल्की-फुल्की प्रेम कहानी से बिलकुल अलग जिसमें आमिर को खासी कामयाबी मिली. इसमें वे ऐसे नौजवान की भूमिका में हैं जो अपनी प्रेमिका से बलात्कार किए जाने के बाद हत्यारा बन जाता है. अंग्रेजी फिल्म 'बैक टू द फ्यूचर' पर आधारित तड़क-भड़क भरी फंतासी फिल्म 'टाईम मशीन' में उन्हें भूमिका देने वाले कपूर कहते हैं, ''मेरा अंतर्मन कहता है कि आमिर निर्देशकों के पसंदीदा बन जाएंगे. मैं अरसे से अभिनेता की तलाश में था. मुझे आमिर में वह प्रतिभा दिखाई दी.''

आमिर में मासूमियत भरा आकर्षण हो सकता है पर एक मायने में यही गुण उन्हें कुछ खास किस्म की भूमिकाओं तक सीमित कर देता है. देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म 'अव्वल नंबर' में सिर्फ इसलिए लिया कि ''मेरी भतीजी उसकी दीवानी थी.'' इस फिल्म में वे आतंकवाद के साये तले भी क्रिकेट खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे हैं. बी. सुभाष की फिल्म 'लव लव लव' में उनकी भूमिका बस नाच-गाने तक ही सीमित है. देवानंद कहते भी हैं, ''फिल्म उद्योग में यह एक नई लहर है. पर लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कई फिल्मों में काम की जरूरत है.''

आमिर खां की मासूमियत ही उन्हें बाकी भीड़ से अलग कर देती है. फिल्मों में तो आज बस धूम मचाते युवकों की भरमार है, कोई भी सीधा-सादा नहीं दिखता

आमिर फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं. उनके सामने 70 फिल्मों के प्रस्ताव आए पर उन्होंने 12 फिल्में ही साइन की है, जिनमें ज्यादातर हल्की-फुल्की प्रेमकथाएं हैं. उनकी अपनी जिंदगी भी ख्वाबी रोमांस सरीखी रही है. उनकी शादी पड़ोस की ही एक लड़की रीना दत्त से हुई है. अरसे तक वे दोनों रूमानी संसार के सपनों में डूबे रहे. आमिर के 21 साल पूरे होते ही दोनों ने अदालत में शादी कर ली. वे चाहते हैं कि रीना की तस्वीरें छपें. पर रीना इससे घबराती हैं. वे शहर के बीचोबीच एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती हैं और रोजाना बस से आती-जाती हैं. आमिर कहते हैं, ''यह उसका अपना फैसला है. मुझे भी यही पसंद है कि वह काम करे. अगर पत्नी आर्थिक रूप से अपने पांवों पर खड़ी न हो तो संबंध बराबरी के नहीं रहते.''

'कयामत...' की उनकी नायिका जुही चावला बताती हैं कि जब फिल्म बन रही थी तो वे हर रोज रीना को चिट्ठी लिखते थे. एक रात उन्होंने रीना को ऊटी से फोन मिलाया पर वे घर पर नहीं थीं. कहीं भी उनका पता न चला. बाहर युनिट के लोग कारों में बैठे बंगलूर जाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे. पर आमिर खां तैयार नहीं हुए. जुही बताती हैं, उन्होंने दो घंटे इंतजार करवाया. वे इस कदर चिंतित थे कि उनकी आंखों में आंसू उतर आए. दरअसल रीना ने भी 'कयामत...' में एक छोटी-सी भूमिका निभाई है. आमिर बताते हैं, ''लाल कपड़ों में वह बहुत सुंदर लग रही थी.''

आमिर अब अपनी मर्जी की जिंदगी भी नहीं जी सकते. अचानक मिली कामयाबी की यही समस्या है. वे कहते हैं, ''लोगों की उम्मीदें इस कदर बढ़ गई हैं कि मुझे सब कुछ सोच-समझकर करना पड़ता है.'' एक तरह से उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में वही भूमिकाएं निभानी होंगी जिनका आज अभाव है. यह भूमिका मासूम किशोर की ही हो सकती है.

—सिमरन भार्गव, बंबई में

'अव्वल नंबर' में क्रिकेट खिलाड़ी; और (दाएं) 'राख' में एक हत्यारा

अशोक सालियन

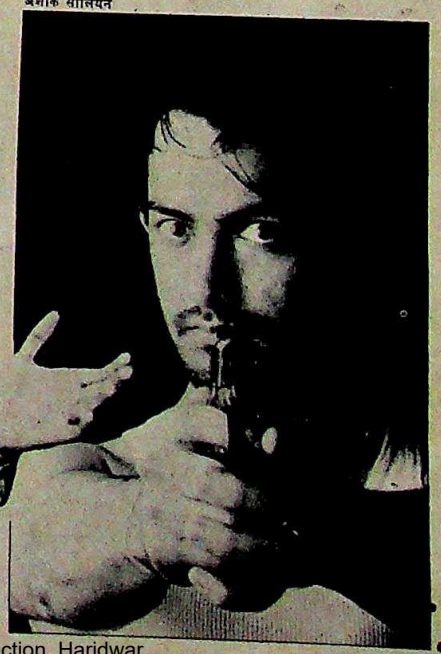

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भगवती जागरण

भक्ति-राग नहीं 'रॉक-भक्ति'

व्यवसायीकरण की नई आंधी ने आयोजनों को खर्चीला बनाया

पिछले करीब दस साल से उत्तर भारत के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक नया मौसम जुड़ गया है और धार्मिक समारोहों की सूची में एक नया समारोह. अगर महीना अक्तूबर, नवंबर या दिसंबर का है और किसी शनिवार की रात आप घर लौट रहे हैं तो इस बात की गुंजाइश लगभग न के बराबर है कि रास्ते में भगवती जागरण के लिए लगाए गए किसी विशालकाय शामियाने की वजह से आपको रास्ता न बदलना पड़े. इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि अगले जागरण पंडाल के लाउडस्पीकरों की 'फायरिंग रेंज' में घुसने से पहले ही इस जागरण की फायरिंग रेंज खत्म हो जाए.

कुल मिलाकर हालत यह है कि दिल्ली हो या पानीपत, कानपुर हो या कांगड़ा, भगवती जागरण अब उत्तर भारत के शहरों और कस्बों की सांस्कृतिक-धार्मिक जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और बदलते वक्त के साथ व्यावसायिक रूप भी ले चुका है.

भले ही किसी फैक्टरी या दुकान के उद्घाटन के मौके पर कराया गया कोई निजी जागरण हो या फिर किसी व्यापारी संघ, मुहल्ला सुधार समिति या किसी 'युवा' मंच द्वारा आयोजित कोई 'विशाल' भगवती जागरण—सब जगह पंडाल में कमोबेश एक जैसा दृश्य ही देखने को मिलता है: सुनहरे या चांदी की चमक वाले भवन में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से संचालित मूर्तियां; सम्मोहित कर देने वाली साइकेडेलिक रोशनियां; 15-20 माइक्रोफोनों से सज्जित एक बड़ा-सा मंच; म्युजिक-सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रिक-गिटार, पियानो-अकॉर्डियन और सैक्सोफोन से लेकर तबले तक से लैस एक या दो दर्जन कलाकार; वीडियो फिल्म बनाने वाले फोटोग्राफर और चिंघाड़ते हुए लाउडस्पीकरों के घेरे में मंत्रमुग्ध होकर झूमते हुए भक्तगण. यह सारा तामझाम लोगों में बढ़ती धार्मिक श्रद्धा का सही बैरोमीटर भले ही न हो पर यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि भगवती जागरण अब एक फैशन और सामाजिक रुतबे की माप-जोख का पैमाना तो बन ही चुका है.

हालांकि तेज सर्दी और बरसात के दिनों को छोड़ लगभग पूरा साल जागरणों का आयोजन चलता रहता है पर मानसून के बाद नवरात्रि के आगे-पीछे वाला तीन महीने का दौर तो अब उत्तर भारत में जागरण का ही मौसम बन चुका है. इन दिनों शायद ही कोई ऐसी रात हो जब किसी शहर-कस्बे में कहीं न कहीं जागरण आयोजित न किया जाता हो.

आमतौर पर भगवती जागरण का कार्यक्रम रात 11 बजे से अगली सुबह 6 बजे के बीच तीन चरणों में पूरा किया जाता है. पहले चरण में 11 बजे से 12 बजे तक एक महंत अपनी मंडली के साथ गणेश पूजन करवाता है और 'जोत' (ज्योति) प्रज्ज्वलित करता है. इस पूजा-अर्चना के बाद 4 बजे सुबह तक भजन और भगवती देवी की स्तुति में 'भेंट' गाने का कार्यक्रम चलता है और अंत में 5.30 बजे तक तारा रानी की कथा सुनाई जाती है. इसके बाद अर्चना और प्रसाद वितरण के साथ 6 बजे जागरण संपन्न होता है. इस प्रक्रिया में दूसरा चरण सबसे विविध और रोचक रहता है और इस चरण के लिए बुलाए गए कलाकारों की लोकप्रियता और फीस के अनुपात से ही जागरण के स्तर को आंका जाने लगा है.

इस होड़ के चलते अब पूरे उत्तर भारत में शायद ही कोई शहर या कस्बा ऐसा होगा जहां हर साल 'विशाल' जागरण का आयोजन कराने वाली कम-से-कम एक संस्था क्रियाशील न हो. पिछले दिनों नवरात्रि

त्यौहार के दौरान दिल्ली में अशोक विहार के दुकानदारों की एक संस्था ने लगातार नौ रात तक नौ जागरण आयोजित करके इस मैदान में एक नया झंडा गाड़ दिया. एक अनुमान के अनुसार इस आयोजन पर 2 से 3 लाख रुपए के बीच खर्च किया गया. इतना पैसा आता कहां से है? जवाब में जागरण शृंखला के आयोजक हीरालाल वर्मा कहते हैं, ''पैसे भेजना तो माता रानी का काम है. वो हुक्म करती है और लोग अपने आप आकर पैसा दे जाते हैं.''

बाद में इस आयोजन के 'मुकाबले' पड़ोसी बस्ती शालीमार बाग के प्राप ड़ीलर संघ ने जिस विशाल पैमाने पे जागरण का आयोजन किया उसे देखकर य लगता था कि इस अकेले आयोजन में ही

भजन गाते नरेंद्र चंचल: ऊंची फीस, बढ़ता बाजार

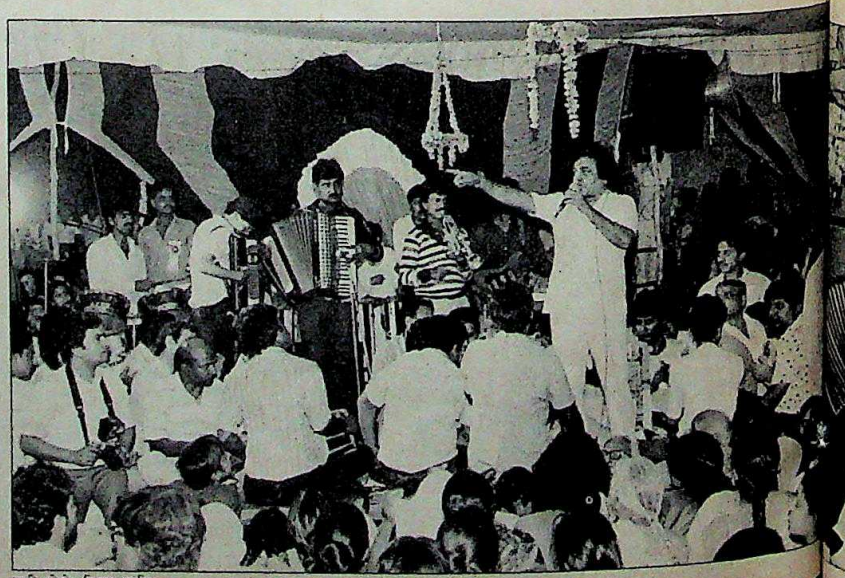

सभी फोटो: विजय शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अशोक विहार के दुकानदारों को पीछे छोड़ने की ठाने हुए थे. एक विशालकाय पार्क में नकली पहाड़ियां बनाकर उनमें लगभग 40 फुट की ऊंचाई पर देवी का भवन बनाया गया और वहां तक पहुंचने के लिए गुफाओं और सुरंगों का लगभग वैसा ही जाल बिछाया गया जैसा वैष्णव देवी की यात्रा के दौरान यात्रियों को देखने को मिलता है. पार्क के बाहर दो किलोमीटर सड़क को चांदनी वाली झाड़ियों, विशालकाय बंदनवारों और लगभग 20 लाउडस्पीकरों से सजाया गया था.

जागरण की इस लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता और उससे जुड़े पैसे का एक नतीजा यह हुआ है कि आज से 10-15 साल पहले तक परंपरागत 'पक्की भेंट' गाने वाली जागरण मंडलियों तक सीमित इस धंधे में

नकली पहाड़ियों में चलते हुए श्रद्धालुः तमाशा और खर्चीली श्रद्धा

अब व्यावसायिक संगीत मंडलियां और फिल्मी कलाकार भी धूम-धड़ाके के साथ कूद चुके हैं. जागरण की घोषणा करने वाले पोस्टरों और साइनबोर्डों पर अब महेंद्र कपूर, सुलक्षणा पंडित, रवींद्र जैन, उषा मंगेशकर, नरेंद्र चंचल, हेमलता, सपना मुकर्जी और शारदा जैसे लगभग दो दर्जन फिल्मी नाम देखे जा सकते हैं. हालांकि ये सभी कलाकार अपनी फीस के आंकड़ों को गोपनीय रखते हैं पर इस धंधे से जुड़े लोगों के अनुसार 3-4 घंटे के एक कार्यक्रम के लिए इनमें से कुछ कलाकारों की फीस, हवाई टिकट और होटल का कुल खर्च 15 हजार से 40 हजार के बीच बैठता है.

भले ही फिल्मी कलाकारों की फीस काफी ऊंची है पर जागरण के धंधे पर अभी भी असली कब्जा उन संगीत मंडलियों का है जो जागरण में गाने के साथ-साथ शादी-ब्याह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रोग्राम पेश करने में माहिर हैं. अकेले दिल्ली में ही ऐसी लगभग 20 प्रमुख मंडलियां हैं जो किसी-न-किसी लोकप्रिय कलाकार के नेतृत्व में चलती हैं. इनमें प्रहलाद, प्रेम भाटिया, बरखा, मीनू चड्ढा, ब्रज रंगीला, गौरी तथा राजन जैसे कलाकारों की मंडलियां इन दिनों लोकप्रियता के मामले में ऊपर गिनी जाती है.

इन मंडलियों के बीच चलने वाली होड़ का परिणाम यह हुआ है कि अब जागरण में गाई जाने वाली पक्की भेटों का स्थान फिल्मी और दूसरे लोकप्रिय गीतों की धुन पर गाए जाने वाले भजन ले चुके हैं. बल्कि इस होड़ में एक दूसरे से बाजी मार ले जाने के चक्कर में कई मंडलियां तो अब 'रॉक' और 'पॉप' धुनों पर भी भजन पेश करने लगी हैं. कुछ महिला कलाकार तो जिस तरह नाचने की हद तक झूमतें हुए इन धुनों पर भजन गाती हैं उसे देखकर यह अंदाज लगा पाना कठिन हो जाता है कि भगवती जागरण हो रहा है या रॉक कार्यक्रम. इस बारे में 'बरखा एंड पार्टी' की बरखा कहती हैं, "मैं राग और रॉक की खिचड़ी के पक्ष में नहीं हूं. पर मार्केट में होड़ और जागरण कराने वालों की बदलती रुचियों के कारण कलाकार सब कुछ करने लगे हैं."

हालांकि पिछले कुछ साल में भगवती-जागरण का खासा व्यवसायीकरण हुआ है पर इसके बावजूद अभी भी ऐसी मंडलियों की संख्या अच्छी खासी है जो एकदम परंपरागत शैली में जागरण करती हैं. इनमें से अधिकांश मंडलियां शौकिया हैं. ऐसी ही एक मंडली के संचालक ब्रिगेडियर कपिल मोहन हैं जो भारत की सबसे प्रमुख शराब निर्माता कंपनी मोहन मीकिंस के प्रबंध निदेशक हैं. वे पिछले दस साल के दौरान अपनी जागरण मंडली के साथ लगभग 500 जागरण बिना फीस लिए कर चुके हैं. कंपनी के लगभग 25 कर्मचारियों की इस शौकिया मंडली में सिंथेसाइज़र, पियानो-अकॉर्डियन, ट्रंपेट, सैक्सोफ़ोन और क्लैरोनेट तथा दूसरे कई साज़ बजाने वाले और झाकियां तैयार करने तथा उनमें भूमिका निभाने वाले कलाकार हैं. यह मंडली हर शाम ब्रिगेडियर मोहन के निवास पर रियाज़ करती है और उन्हीं के साथ अपनी छुट्टियों के दौरान दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और दूसरे पड़ोसी राज्यों में जागरण के लिए जाती हैं. मंडली की खासियत यह है कि इसके सभी भजन शास्त्रसम्मत हैं और उन्हें मोहन के व्यक्तिगत निर्देशन में लिखा व संगीतबद्ध किया गया है.

अपने जागरण कार्यक्रमों के बारे में मोहन बताते हैं, "हम केवल उन्हीं संस्थाओं के जागरण में जाते हैं जो पूरी तरह श्रद्धालु हों और फिजूलखर्च न हों. मैं हर जागरण में इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं कि हमारे लाउडस्पीकरों की आवाज पंडाल और उसके आसपास के थोड़े से इलाके तक ही सीमित रहे ताकि उन लोगों की नींद खराब न हो जो घर में सोना चाहते हैं."

मगर जिस तेजी से भगवती जागरण का व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है उसे देखते हुए यह कह पाना कठिन है कि शौकिया और श्रद्धालु जागरण मंडलियां कब तक मैदान में टिकी रह पाएंगी—खासकर तब जबकि जनता की रुचि राग के बजाय 'रॉक' में बढ़ती जा रही हो.

—विजय क्रान्ति

अपनी मंडली के साथ (माइक पर) कपिल मोहनः शास्त्रसम्मत गायन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साधारण लोग

ढोंगी राजनीति बेनकाब

कत्ल दर कत्ल त्रासदी भोगते समाज का चित्र

नई दिल्ली के बोट क्लब पर कृषि भवन के पीछे तमाशबीन बाबुओं की एक भीड़ दायरा बनाए खड़ी है. दायरे के बीचोबीच खाली जगह पर एक सिख आतंकवादी हाथ में कृपाण लेकर एक सिख युवक को धमका रहा है. पास में ही हवा में त्रिशूल लहराता हुआ एक भगवाधारी नेता एक हिंदू को समझा रहा है कि उसे भी हथियार उठा लेना चाहिए. लेकिन वह हिंदू यह नहीं समझ पा रहा कि किसके खिलाफ उसे हथियार उठाना चाहिए और क्यों?

यह एक दृश्य है गुरशरण सिंह के नाटक 'साधारण लोग' का जिसे दिल्ली के निशांत नाट्यमंच ने पिछले पखवाड़े बोट क्लब के खुले मैदान में मंचित किया. यह नाटक पंजाब की उस मौजूदा त्रासदी पर एक तीखी टिप्पणी है जिसे पंजाब की जनता पिछले कई साल से कत्ल दर कत्ल भोगती चली आ रही है. नुक्कड़ नाटक की सरल शैली और दो-टूक भाषा में खेले जाने वाले इस नाटक की कहानी एक गांव में रहने वाले रामलाल और राम सिंह से शुरू होती है जो अच्छे पड़ोसियों की तरह भाईचारे के वातावरण में रहते चले आ रहे थे पर राज्य में हिंसा के चलते वे बिना सोचे-समझे एक दूसरे को अपना दुश्मन मान बैठते हैं.

समस्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गलियारों का बेधड़क मुआयना करती हुई यह कहानी रामलाल और राम सिंह को आखिर में फिर से अपने गांव के उसी चबूतरे पर ला खड़ा करती है जहां बरसों तक प्यार से उठने-बैठने के बाद वे कुछ दिन पहले एक दूसरे का खून पीने को उतर आए थे. वे इस असलियत को समझ चुके हैं कि सारा झगड़ा उन राजनीतिकों की चाल का नतीजा है जो अपनी राजनीति की रोटी सेंकने में लगे हुए हैं.

नाटक की असली ताकत उसकी सादगी है. मसलन, जब रामलाल और राम सिंह के झगड़े के बाद इलाके में कर्फ्यू लगने पर चार रुपए किलो वाले टिंडे का भाव रातोरात दस रुपए किलो हो जाता है तब कारण पूछने पर फेरीवाला उन्हें समझाता है कि कर्फ्यू-पास बनवाने के लिए नेताजी को चढ़ाई जाने वाली भेंट और सीआरपीएफ के सिपाहियों को दी जाने वाली घूस के बाद टिंडे जैसी सब्जी भी कैसे 'इज्जतदार' चीज बन जाती है. यह बताते हुए उसका यह बयान सारे किस्से को साफ कर देता है कि "जब दो बेवकूफ आपस में लड़ते हैं तब फायदा तो सयानों के ही हिस्से आता है."

यह नाटक पंजाब के कई गांवों में खेला जा चुका है. 'निशांत' के संचालक और इस नाटक के निर्देशक शम्सुल इस्लाम बताते हैं, "कई बार ऐसा हुआ कि किसी गांव के मैदान में या किसी कस्बे के चौराहे पर चलते हुए नाटक को रोकने के लिए पुलिस आ धमकी लेकिन दर्शकों की भीड़ ने एक भी स्थान पर पुलिस की नहीं चलने दी." शौकिया स्तर पर नाटक खेलने वाली इस मंडली की एक खासियत यह है कि पिछले 17 साल से यह हर रोज कम से कम एक नाटक का मंचन जरूर करती आ रही है. और दूसरी खासियत यह कि निशांत के सभी नाटक सामाजिक संदेश लिए होते हैं.

'साधारण लोग' के अलावा निशांत के तीन अन्य नाटक गड्डा', 'सबसे सस्ता गोश्त' (गुरशरण सिंह) और 'औरत' इन दिनों खास चर्चित हैं. कृश्न चंदर की कहानी पर आधारित 'गड्डा' अफसरशाही पर कटाक्ष है तो '...गोश्त' सांप्रदायिक सोच पर तीखा प्रहार है. खुमैनी के ईरान में इन दिनों 12 साल की जेल भुगत रही एक ईरानी प्राध्यापिका द्वारा लिखित नाटक का हिंदुस्तानी रूपांतर 'औरत' भी औरत के प्रति दुनिया भर में चल रहे दोगले रवैये पर आंखें खोल देने वाली टिप्पणी है. और जहां तक 'साधारण लोग' की बात है, यह एक राष्ट्रीय समस्या पर साधारण लोगों के दरवाजों तक जाकर उन्हीं की साधारण भाषा में की गई ऐसी सटीक विवेचना है जो जनता को गुमराह करने वालों की चालों को बेपर्दा करती है.

—विजय क्रान्ति

(बाएं से) शम्सुल इस्लाम, विजयपाल सिंह, घनश्याम और जितेंद्र: राजनीति की हिंसा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

वृद्धाओं की वेदना

लालच देकर की गई नसबंदी के बाद भी पूरा पैसा नहीं मिला

कड़े मार्ग निर्देशों और मानवीय दृष्टिकोण का ख्याल रखे बिना तय किए लक्ष्य और कोटे कहर बरपा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की कई बूढ़ी हरिजन महिलाओं को यही कड़वी सचाई भोगनी पड़ी. अफसरशाही की ऐन निष्ठुरता भरी तर्ज पर सात हरिजन महिलाओं की नसबंदी ऐसे लुभावने वायदे देकर की गई, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया. यह क्रूरता तो उस समय और भी भयानक दिखने लगी जब पता चला कि उक्त सातों महिलाओं को रजोनिवृति की अवस्था पार किए अरसा बीत चुका है.

इससे राज्य सरकार के उन दावों की कलई खुल जाती है कि उसने पिछले साल बंध्याकरण का अपना कोटा 114 फीसदी पूरा किया है. दरअसल इससे ऐसे सभी सरकारी आंकड़े संदेह के दायरे में आ जाते हैं.

ये सातों महिलाएं अलीगढ़ जिले के हाथरस शहर से करीब 5 किमी दूर सोखना गांव (आबादी 3,000) की हैं. ये सभी अफसरशाही दिमाग की उस करामात की शिकार हुई हैं जिसके तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम को इंदिरा आवास योजना (हरिजनों को सस्ते आवास मुहैया कराने) से जोड़ दिया गया ताकि बंध्याकरण के लिए निर्धारित कोटा आसानी से पूरा किया जा सके. गांव में मकान बनाने के लिए रकम का लालच देकर इन महिलाओं का बंध्याकरण स्थानीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में किया गया. चार को तो किसी तरह आधी रकम मिल गई पर तीन महिलाएं अभी भी पैसा पाने की आस में हैं.

ये महिलाएं हैं—53 वर्षीया कलावती, 55 वर्षीया अशरफी देवी, 56 वर्षीया कस्तूरी देवी, 60 वर्षीया भगवान देवी, 62 वर्षीया लीलावती, 65 वर्षीया पंचो और 70 वर्षीया रज्जो देवी. उनसे हुई बातचीत और उनके परिवार नियोजन संबंधी पहचान पत्रों में दिए ब्यौरों से उनके साथ हुए क्रूर मजाक का पर्दाफाश होता है. इन पर कहर बरपा इसलिए हुआ क्योंकि जिला अधिकारियों को अपना निर्धारित कोटा पूरा करना था जबकि हाथरस के अधिकारी बढ़-चढ़कर नतीजे दिखाने के इच्छुक थे ताकि लगे हाथ उन्हें भी एक या दो प्रोन्नतियां मिल जाएं.

इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की जरूरत थी. सोखना में उन्हें ऐसे दो व्यक्ति— डॉ. बाबूलाल और डॉ. एम.आर. निर्मल हाथोहाथ मिल गए. गांववालों को उन पर पूरा भरोसा भी था. मार्च 1986 में स्थानीय खंड विकास अधिकारी और हाथरस में माहो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर इन दोनों डॉक्टरों ने सातों महिलाओं को यह बताकर बंध्याकरण के लिए राजी कर लिया कि इसके बदले उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत गांव में एक कमरे का मकान बनाने के लिए 6,000 रु. दिए जाएंगे.

रजोनिवृत्ति की अवस्था पार कर गई सात हरिजन महिलाओं को रुपए का लालच देकर बंध्याकरण के लिए राजी किया गया

गणेशी लाल की पत्नी भगवान देवी इस झांसे में सबसे पहले आई. 5 मार्च को हाथरस के बागला अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ. भगवान देवी याद करती है, "मैं बीमार पड़ गई और मुझे महीना भर अस्पताल में ही रहना पड़ा. आज भी मैं सीधा होकर नहीं चल सकती. उन्होंने मेरा जीवन नकारा कर दिया." वह कहती है कि डॉ. बाबूलाल ने ही उसे ऑपरेशन के लिए प्रेरित किया. 6,000 रु. में से उसे 3,000 ही मिले. वह कहती है, "मकान पूरा करने के लिए 1,000 रु. तो हमें अपनी जेब से खर्च करने पड़े. बाकी रकम वही लोग हड़प गए जो मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए थे. पर उन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी." अधिकारियों के फरेब की कहानी उन्हें माहो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के हस्ताक्षर से दिया गया पर्चा (संख्या—352/12) भी कहता है जिसमें उम्र का खाना तो एकदम खाली छोड़ दिया गया है.

कस्तूरी देवी का मामला तो और भी दुखद है. उसके पति तेज सिंह की मृत्यु 1982 में हो गई थी. इस विधवा ने बताया कि डॉ. बाबूलाल ने गांव में मकान बनवाने का लालच देकर उसे बंध्याकरण के लिए राजी कर लिया. 7 मार्च को उसका ऑपरेशन हुआ. फरेब की हद तो यह कि उसका पंजीकरण हाथरस ब्लॉक के ही गांव नूरपुर के परमसुख की पत्नी श्रीदेवी के नाम पर किया गया. कस्तूरी कहती है, "मैं एक महीने से ज्यादा अस्पताल में बीमार पड़ी रही. वे मुझसे बार-बार कहते रहे कि जल्दी ही मुझे पहचान पत्र दे दिया जाएगा पर कभी दिया नहीं गया. ऑपरेशन के बाद मैंने दवा-दारू पर 500 रु. खर्च किए. मकान बनाने की रकम तो दूर, मुझे इलाज के लिए भी कोई पैसा नहीं मिला." कस्तूरी के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साथ बातचीत के दौरान डॉ. बाबूलाल भी मौजूद थे. उन्होंने माना कि कस्तूरी का कहना सही है.

फिर डॉ. बाबूलाल गांव में अपने कथित प्रतिद्वंद्वी डॉ. निर्मल द्वारा प्रेरित बंध्याकरण के ऐसे ही मामलों को बताने लगे, मानो वे इस फरेब को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हों. बाबूलाल की पत्नी रज्जो देवी का मामला डॉ. निर्मल के खाते में है. पीड़ितों से 'इंडिया टुडे' की बातचीत के दौरान डॉ. निर्मल भी मौजूद थे. 31 मार्च को रज्जो देवी का ऑपरेशन हुआ. उसका सबसे छोटा बेटा 15 साल का है और दो बड़े बेटे शादीशुदा हैं. रज्जो को भी ऑपरेशन के बाद माहो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से जो पहचान पत्र (संख्या-355/14) जारी हुआ, उसमें उम्र का खाना खाली है. वह कहती है, "ऑपरेशन ने मेरे शरीर को जर्जर बना दिया है. मुझे सिर्फ 3,500 रु. मिले. मकान के लिए बाकी रकम हमें अपनी जेब से खर्च करनी पड़ी."

डॉ. निर्मल मानते हैं कि डॉ. बाबूलाल द्वारा ऑपरेशन के लिए प्रेरित की गई महिलाओं समेत ज्यादातर महिलाओं को 6,000 रु. के बजाय 4,000 रु. ही मिले. वे बताते हैं, "बाकी रकम साहबों ने बांट ली. हमें तो थोड़ी ही मिली."

सभी फोटो प्रभात पांडेय

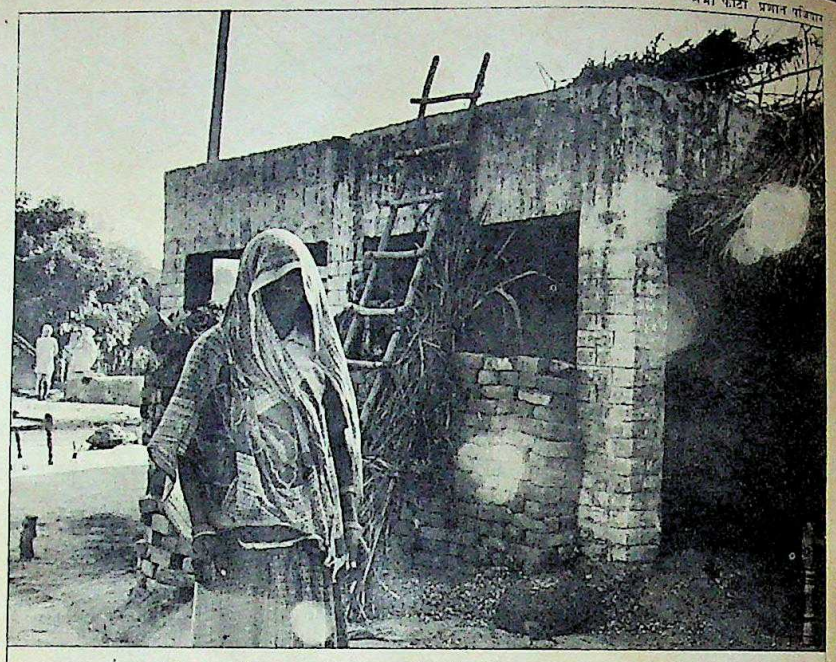

62 वर्षीया लीलावती कहती है कि बंध्याकरण के बाद उसे 6,000 रु. के बदले सिर्फ 3,000 रु. मिले. ऑपरेशन के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी और अब वह मेहनत-मजदूरी नहीं कर सकती

परम सिंह की पत्नी लीलावती (पहचान पत्र संख्या—355/17) का ऑपरेशन 7 मार्च को हुआ. उसे बाबूलाल ने बंध्याकरण के लिए उकसाया था. वह कहती है, "मुझे 3,000 रु. मिले जिसमें से 500 रु. मैंने डॉ. बाबूलाल को दिए. बाकी 3,000 किसकी जेब में गए, मैं नहीं कह सकती." ऑपरेशन से उसकी हालत खराब हो गई.

ऐसी क्रूरता का एक और मामला अशरफी देवी का है. उसका बंध्याकरण 31 मार्च को हुआ. माहो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा जारी उसके पहचान पत्र पर 353/15 संख्या अंकित है. पर आज तक उसे मकान नहीं मिला. अशरफी शिकायत करती है, "डॉ. निर्मल ने मुझे बंध्याकरण पर मजबूर किया. ऑपरेशन के बाद उन्होंने कोई मदद नहीं की." पर डॉक्टर का कहना है कि उसे पैसा न जाने क्यों नहीं मिला.

मार्च 1986 में बंध्याकरण करवाने वाली एक वृद्ध विधवा पंचो देवी है. हाथरस के एक इंका नेता मूलचंद नीम के अनुसार उसके पति खेचरमल की मृत्यु 1970 में हो गई थी. पिछले महीने लखनऊ में हुए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन में इन मामलों को उठाने वाले नीम ने ही पंचो देवी का मामला 'इंडिया टुडे' को बताया.

अन्याय के अलावा वहां डर भी व्याप्त है. आठ साल के सबसे छोटे बेटे की मां कलावती गांव के दोनों डॉक्टरों और अपने पति रामदयाल की गैर-हाजिरी में मुंह खोलने को तैयार नहीं हुई. उस समय रामदयाल खेत में था. कलावती का ऑपरेशन 7 मार्च को हुआ. दूसरों की तरह उसे भी मकान बनाने के लिए 3,000 रु. ही मिले.

कुछ लोगों ने इन मामलों में न्याय दिलाने के लिए लड़ने का प्रयास किया है. हाथरस के एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता जालिम सिंह ने इन मामलों की खबर जिला अधिकारियों तक पहुंचाई. पर उन्हें नाकामी ही हाथ लगी.

इंदिरा आवास योजना और परिवार नियोजन कार्यक्रमों में हुए घपले का एक और सूचक 45 वर्षीय रामबेटी का अनोखा मामला है. उसके पास बंध्याकरण के एक नहीं बल्कि दो पहचान पत्र हैं. उसका पहला ऑपरेशन 5 मार्च 1986 को हुआ और पहचान पत्र भी मिला. तुरंत बाद उसे मकान बनाने के लिए 3,000 रु. भी मिल गए पर दिसंबर 1987 में उसने एक बेटे को जन्म दिया. रामबेटी ने 19 अप्रैल 1988 को फिर ऑपरेशन करवाया और उसे दूसरा पहचान पत्र भी दे दिया गया. उसके मामले में अधिकारियों को शायद दो अलग-अलग वर्षों में अपना कोटा पूरा करने में मदद मिली.

वैसे, इस साल ऐसे मामलों के बढ़ने का भी अंदेशा है क्योंकि हर ब्लॉक में हरिजनों को मकान मुहैया कराने का कोटा बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है. सरकारी सूचना के अनुसार 1986 में जब इन सातों महिलाओं का ऑपरेशन हुआ उस समय पूरे हाथरस ब्लॉक के लिए आवास योजना के तहत 26 मकान मुहैया कराने का कोटा तय था. लेकिन अब 89 ग्राम पंचायतों वाले इस ब्लॉक का कोटा बढ़ाकर 223 कर दिया गया है. एक जिला अधिकारी ने माना, "ऐसे मामले निगरानी के अभाव में होते हैं और कभी-कभी तो कोटा पूरा करने के चक्कर में भी होते हैं."

विचित्र बात तो यह है कि पीड़ित लोग और गांव के नीमहकीम जहां आपस में उलझ रहे हैं, वहीं जिला अधिकारी और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर छुट्टे घूम रहे हैं और तबादले के बाद शायद नई जगह पर भी अपना यही क्रूर खिलवाड़ जारी रख सकते हैं.

—दिलीप अवस्थी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

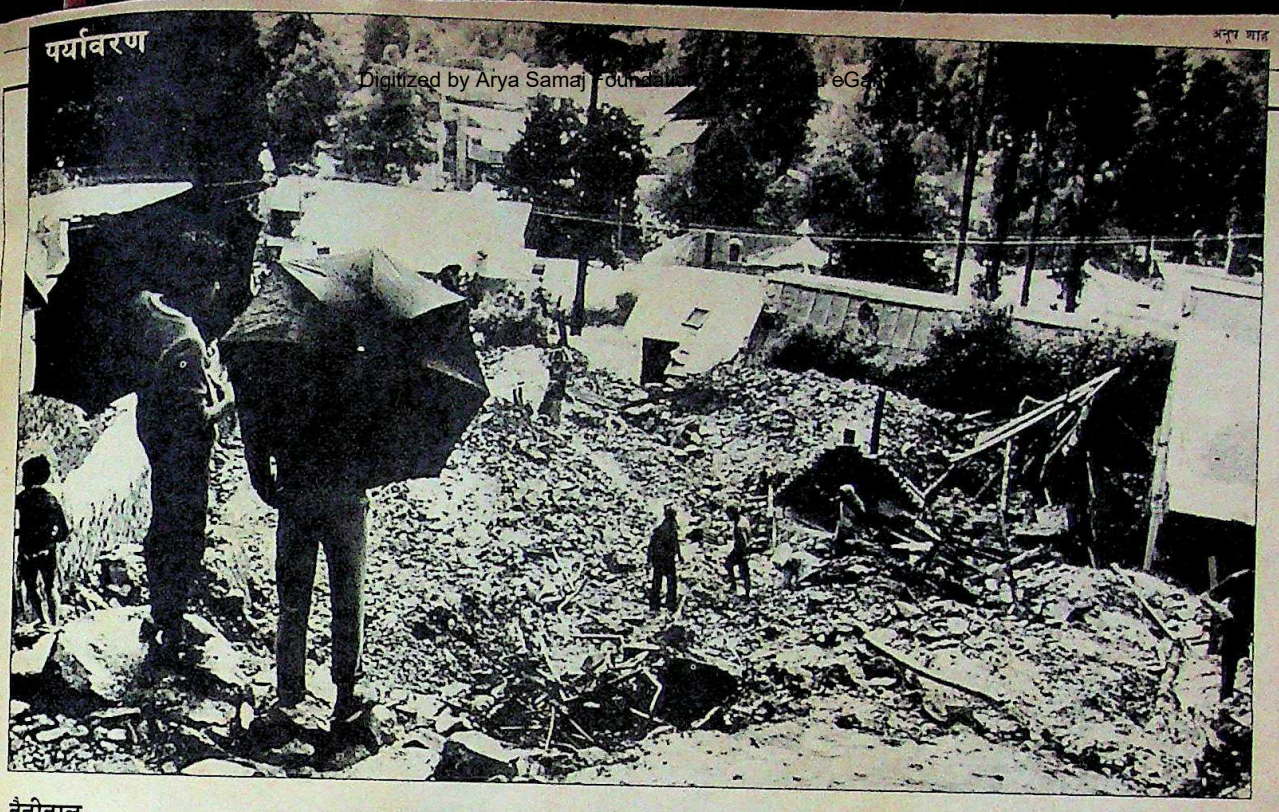

अनूप शाह

भूस्खलन के मलबे की सफाई

नैनीताल

खिसकती चट्टानों की चोट

अवैध भवन निर्माण और अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों से समस्या गंभीर

अपनी खूबसूरत झील के लिए प्रसिद्ध, 1939 मीटर की ऊंचाई पर बसा नैनीताल देश के लोकप्रिय पहाड़ी पर्यटन स्थलों में से एक है. यहां सीधी चढ़ाई वाली 'शेर-का-डांडा'—स्नो व्यू हिल—पर घने जंगल के बीच एक पुराना सुनसान चर्च है. इस चर्च की पूर्वी खिड़की 1880 के एक विनाशकारी भूस्खलन में जिंदा दफन हुए 151 लोगों की याद में बनाई गई थी. इस गुमनाम-से स्मारक की तरफ लोगों का ध्यान अभी हाल में तब गया जब कुछ महीने पहले हुए भूस्खलन ने उस हादसे की याद दिला दी. इस पूरे पहाड़ी स्थल के भविष्य के प्रति ही लोग चिंतित हो उठे.

जुलाई में नैना पहाड़ी (2610 मीटर) से हुए भूस्खलन से यहां के लोगों में एक दहशत-सी फैल गई थी. एक अंदाज के अनुसार करीब 50,000 घनमीटर चट्टान और मिट्टी के खिसकने से दर्जनों घर तबाह हो गए. यह मलबा शहर के उत्तर-पूर्वी सिरे पर स्थित पहाड़ी की तलहटी के घनी आबादी वाले हिस्से के बिलकुल नजदीक ही पहुंच गया था. पहाड़ी के ऊपरी भाग में मलबे को रोकने के लिए बनाई गई दीवार पर अभी भी 15,000 घनमीटर मलबा अटका हुआ है.

कुमाऊं विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष 38 वर्षीय डॉ. अजय सिंह रावत कहते हैं, "इसमें कोई शक नहीं कि यह पहाड़ी धीरे-धीरे धंस रही है." दूसरे भूवैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है. रावत बताते हैं कि नैना पहाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में 65 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर गहरी दरार पड़ी हुई है.

खतरे की पहली घंटी पिछले सितंबर में बजी, जब नैना पहाड़ी से खिसकी चट्टानों ने करीब 100 पेड़ों को उखाड़ फेंका था. कुछ महीनों बाद 11 मार्च को मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन से मलबा घनी आबादी वाले इलाके तक जा पहुंचा था. लेकिन ज्यादा नुकसान, 4,5 और 6 जुलाई को हुए भूस्खलन से ही हुआ. 6 जुलाई को सुबह लगभग 6.30 बजे मेलरोज और बुकहिल इलाकों की 61 इमारतों पर चट्टानों और पत्थरों की भारी बौछार हुई जिससे 470 परिवार आहत हुए. कुमाऊं विश्वविद्यालय के बुकहिल छात्रावास और स्विस होटल को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची.

कुमाऊं विश्वविद्यालय को तो मार्च में हुए भूस्खलन से ही चेत जाना चाहिए था जब होस्टल के लड़के बाल-बाल बच गए थे. छात्र संघ के अध्यक्ष एम.जी. गोस्वामी बताते हैं, "चूंकि हम सब इम्तहान की तैयारी में जगे हुए थे इसलिए चट्टानें गिरने की आवाज सुनकर होस्टल से बाहर आ गए." उनके बाहर आने के ठीक बाद ही एक बैरक मलबे के नीचे दब गई. होस्टल के वार्डन जे.सी. जोशी के अनुसार, "खुशकिस्मती से मार्च और जुलाई में हुए भूस्खलन के वक्त लड़के कमरों में नहीं थे, वरना बड़ी त्रासदी हो जाती."

पर्यटन पर टिकी नैनीताल की अर्थ-व्यवस्था अब डगमगाने लगी है. नैनीताल में मोमबत्ती का व्यापार करने वाले एक व्यापारी शेर सिंह भी कहते हैं, "मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस साल पूजा के दौरान हमारी बिक्री पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी कम हुई." कलकत्ता की एक कंपनी के अधिकारी संदीप मजूमदार बताते हैं कि इन गर्मियों में वे अपने परिवार के साथ नैनीताल आए थे. काम के सिलसिले में पिछले महीने उन्हें फिर यहां आना पड़ा. लेकिन इस बार उनकी पत्नी ने साथ आने से यह कहकर इनकार कर दिया कि "वहां भूस्खलन में दबकर मैं मरना नहीं चाहती."

भूस्खलनों का यह मनहूस सिलसिला 1880 में शुरू हुआ था. नैनीताल के बीचो-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बीच बने सुविख्यात खेल के मैदान स्नो व्यू हिल से गिरे मलबों के झील के एक हिस्से में भरने के कारण बने. स्नो व्यू हिल, जहां तकरीबन 50 होटल और नैनीताल के विख्यात पब्लिक स्कूल बने हैं, अब भी सुरक्षित नहीं है. लेकिन अधिकारियों का मानना है कि 1986 में रोपवे से इस पहाड़ी को थोड़ी मजबूती मिली है.

भूवैज्ञानिक कारणों के अलावा सरकार और प्रशासन की अदूरदर्शिता भी मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार है. ब्रिटिश सरकार ने नैना पहाड़ी की मजबूती के लिए वृक्षारोपण के अलावा नैनीताल के गिर्द पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर मलबे को रोकने के लिए अस्थायी दीवारें बनाई थीं. बारिश के पानी का रुख झील की ओर करने के लिए 56 किमी लंबी 71 नालियां बनाई गईं. 1911 से 1930 तक के रिकार्ड में इनके रखरखाव का विवरण है. 1930 में स्नो व्यू हिल और नैना पहाड़ी पर भवन निर्माण वगैरह पर रोक लगा दी गई, जिसे 1953 में एक बार फिर बढ़ा दिया गया.

लेकिन '70 के दशक में अतीत के ये सुरक्षात्मक उपाय जल्द ही भुला दिए गए. पर्यटकों और स्थानीय आबादी के बढ़ते दबाव (1961 में यहां की जनसंख्या सिर्फ 25,000 थी जो अब 50,000 हो गई. इसके अलावा एक लाख आबादी अस्थायी है) के कारण 1970 में नैना पहाड़ी पर निर्माण दोबारा शुरू हो गया. और 1980 के बाद, खासकर 1986 के बाद तो भवन निर्माण का यह सिलसिला बहुत तेज हो गया. यहां तक कि बहुमंजिले होटल भी बन गए.

यहां बनाई जाने वाली किसी भी इमारत की ऊंचाई 25 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन बृहत्तर नैनीताल विकास प्राधिकरण (बृनैविप्रा) ने 35 फुट ऊंची इमारत बनाने की अनुमति दे दी है. 1950 में नैना पहाड़ी पर महज दो बंगले थे आज कम-से-कम 500 भवन देखे जा सकते हैं.

नैना पहाड़ी के ऊपर माल क्षेत्र में 1976 में किलबरी मोटर रोड के निर्माण से भी पहाड़ी को खतरा बढ़ा है. लेकिन नैनीताल के आयुक्त और 'बृनैविप्रा' के अध्यक्ष ओ.एन. वैद्य इससे सहमत नहीं, "इस तर्क में जरा भी दम नहीं है. 1880 में स्नो व्यू हिल के भूस्खलन का कारण तो किसी तरह का निर्माण या विस्फोट नहीं था. यह तो महज भूगर्भीय कारणों से था."

लेकिन 'बृनैविप्रा' यहां के सबसे खतरनाक इलाके —26 नंबर नाले के किनारे— बिना इजाजत के बने लगभग 100 अवैध मकानों की ओर से आंखें बंद किए बैठा है.

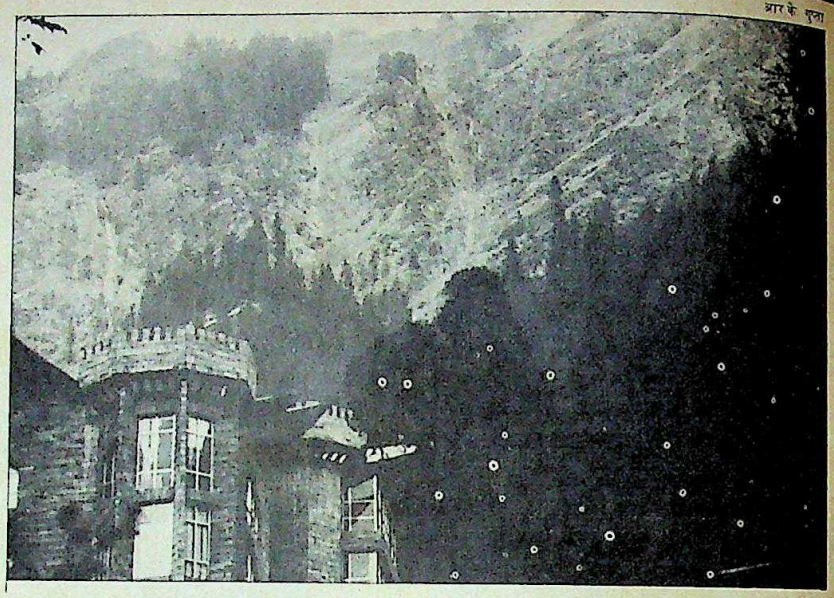

नैना पहाड़ी पर पड़ी दो दरारें

जुलाई के भूस्खलन से साफ हो गया था कि नैना पहाड़ी धीरे-धीरे धंसती जा रही है

वैद्य कहते हैं, "हमने इसे असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है. इसके बावजूद यदि अवैध निर्माण चालू रहता है तो इसकी जिम्मेदारी मकान मालिक पर होगी. दूसरे, हमने मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दायर किए हैं, और आगे भी करेंगे."

लेकिन यहां के निवासी बताते हैं कि किस तरह पिछले साल पक्का तिमंजिला होटल बनाने की इजाजत दी गई. खुद 'बृनैविप्रा' नैना पहाड़ी की शेरवानी चोटी पर चार मंजिले मकानों की एक परियोजना पूरी करने जा रही है. अरमादालरे कंपाउंड में बहुमंजिले निजी फ्लैटों का निर्माण मई से शुरू हो चुका है. और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के नजदीक एक बहुमंजिला होटल भी बन रहा है. इन योजनाओं को 'बृनैविप्रा' मंजूरी दे चुका है. वह भी तब जब यह पहाड़ी 1930 से ही खतरनाक क्षेत्र घोषित है.

नए जिलाधिकारी पी.डी. सुधाकर मामले की गंभीरता को समझ गए लगते हैं, "इस असुरक्षित पहाड़ी पर दबाव कम करने के लिए हम अवैध निर्माण बंद करवा देंगे." जिला अधिकारियों का भी दावा है कि नैना पहाड़ी पर सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं. अपर माल क्षेत्र में तीन सतहों पर दीवारें बना दी गई हैं. और 26 नंबर नाले के किनारों को ऊंचा करके उसके मुहाने पर तारों की जाली लगा दी गई है. सुरक्षात्मक उपायों के प्रभारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एम.जे. खां कहते हैं, "यदि बड़ा भूस्खलन होता है तो ये उपाय बेकार साबित होंगे."

कुमाऊं विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. के.एस. वाल्दिया ने, जिनसे स्थानीय प्रशासन ने समस्या का अध्ययन करने का आग्रह किया था, कुछ स्थायी सुरक्षात्मक उपाय सुझाए हैं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खूनी नाले पर बने लौह जाल की तरह की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है. पहाड़ी के ऊपर तथा क्षतिग्रस्त भागों में दरारों को डामर से जोड़ने का भी उनका सुझाव है. भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञ ज्ञानेश्वर पंत ने चट्टानों और पहाड़ियों को बांधने की राय दी है. वैद्य कहते हैं, "ऐसी बड़ी योजनाओं के लिए समय ही नहीं, कई करोड़ रुपए भी चाहिए. हम अब ऐसे उपायों की तलाश में हैं जो सस्ते भी हों और अपेक्षित परिणाम देने वाले भी."

लेकिन असली सवाल है कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. मधु नायल का, "क्या तब तक हम जिंदा रहेंगे?"

नैनीताल फिलहाल खतरों से घिरा हुआ है. सुधाकर भी मानते हैं कि इन सर्दियों का हिमपात और अगली बरसात ही नैना पहाड़ी की मजबूती की असली परीक्षा होगी. और पहाड़ी ही नहीं, इस पूरे खूबसूरत पहाड़ी स्थल का अस्तित्व भी इस बार दांव पर है.

—दिलीप अवस्थी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपन्यास

दोहरे मूल्यों वाला जीवन

तिरस्कृत नारी के अंतर्द्वंद्वों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

छत पर अपर्णा
उपन्यास
इला डालमिया
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,
कीमत : 31 रु.

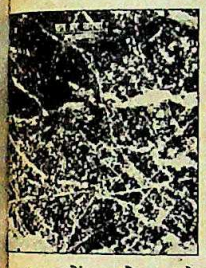

इला डालमिया का उपन्यास 'छत पर अपर्णा' एक सुसंपन्न परिवार में जन्मी और परंपरागत मूल्यों में पली-बढ़ी अंतर्मुखी युवती अपर्णा की कहानी है. उसके परिवार में कठोर और अनुशासनप्रिय पिता है जिसका परिवार पर दबदबा है. स्नेही, धार्मिक विचारों तथा कर्मकांड में पूर्ण विश्वास रखने वाली मां है जो अपने पति को ही अपने ब्रह्मांड की धुरी समझती है. एक बहिर्मुखी बहन है जो अपर्णा की अंतरंग मित्र भी है. बड़ी बेटी होने के कारण उसे परिवार की सभी वर्जनाओं को झेलना पड़ता है, इनमें से कुछ अंकुशों का प्रभाव तो छोटी बहन को छू भी नहीं पाता.

अपर्णा का प्रथम प्रेम कालेज में एक सहपाठी मनु से होता है जिसके बारे में उसे बाद में पता चलता है कि वह पहले से ही विवाहित है और एक बच्चे का पिता भी. मनु उससे यह बात नहीं कहता. यह अपर्णा की चारित्रिक कमजोरी ही है कि वह उसे अपने सान्निध्य में रहने से मना भी नहीं कर पाती. इसी बीच जब वह मनु के झूठ और छिपाव से छटपटा रही थी, उसकी मुलाकात जाने-माने कलाकार सिद्धार्थ से होती है जो उम्र में उससे आठ-दस साल बड़ा है. वह विवाहित है, किंतु आपसी अनबन के कारण अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता. सिद्धार्थ के प्रणय निवेदन को अपर्णा अस्वीकार नहीं कर पाती तथा वह अपने माता-पिता और परिवार की मर्जी के बिना पहले उसके साथ में रहने लगती है और बाद में उससे शादी भी कर लेती है. जल्द ही सिद्धार्थ की रुचि अपर्णा में कम होती जाती है, जो अपने आपको अपनी मां की तरह, पति की पसंद-नापसंद में पूरी तरह से ढाल चुकी है/अब उसकी रुचि अपने एक पुरुष मित्र और एक महिला प्रशंसिका के प्रति बढ़ जाती है. अपर्णा टूट जाती है. किंतु यह सिद्धार्थ के प्रति उसके प्रेम की पराकाष्ठा ही है. उसके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उसे नहीं, दूसरों को ही उत्तरदायी ठहराती है, या शायद ऐसा कर अपने को बहलाती है.

अपर्णा की कहानी एक ऐसी नारी की कहानी है, जो मन से तो परंपरागत है, परंतु या तो अपनी परिस्थितिवश या फिर अपनी भूल से वह एक अति आधुनिक परंपरा से अति दूर जीवन जीती है. मन में चाहती है कि उसके प्रेम का कोई और भागीदार न हो परंतु स्वयं किसी और के प्रेम को अपनाती है. अपर्णा के दो मूल्यों के बीच जीने से उत्पन्न इस अंतर्द्वंद्व की यह कहानी अपर्णा की ही जुबानी है. हालांकि यह क्रमबद्ध नहीं है, और रह-रहकर

> **"कैसा हो कि लाल मिर्च को खूब-खूब महीन पीसा जाए—पीसा जाए महीन और मिलाया जाए काजल में. काजल उन कजरारी आंखों में लगा दिया जाए जो सिद्धार्थ का पीछा करती हैं"**
>
> **इसी किताब से**

विखराव का आभास कराती है. बल्कि शुरू में तो पाठक के लिए यह समझना थोड़ा कठिन हो जाता है कि दो या उससे अधिक समय की घटनाएं एक साथ क्यों कही जा रही हैं. लेकिन फिर भी पाठक की रुचि अपर्णा के साथ होने वाली घटनाओं में तथा उसकी मनःस्थिति में बनी रहती है, और वह समझ पाता है कि उसकी अंतर्दशा का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है.

अपर्णा अपनी वह व्यथा-कथा सुनाती है— छत पर घूमते हुए. छत— जिसके आंचल तले कई घटनाएं जन्म लेती हैं, पलती हैं तथा पनपती हैं. लेखिका ने छत को एक नए रूप में, एक अंतरंग मित्र, एक अंतरंग सौहार्द्र के रूप में दर्शाया है. छत का नया प्रतीक-रूप लुभावना एवं नयापन लिये है.

जहां लेखिका ने छत को एक नया प्रतीक दिया है, वहीं इस उपन्यास में कहीं-कहीं भाषा का प्रयोग भी एक नए, निराले रूप में किया है. भाषा का नई तरह से प्रयोग कहीं-कहीं तो बहुत ही अजीब लगता है और कहीं-कहीं बहुत आकर्षक बन पाया है. कुछ प्रयोग जैसे—'तुम चुपाती क्यों नहीं', 'फिर आंखें खोल-खोल यहां कौन है, कौन है', 'ललित अपने से ही सिलटता रहा', 'लड़की भी घूमकर प्यार करने लगी, 'कभी चंटइपन से सटक लेती है', 'वह विदेश जाने को है'— और ऐसे कई प्रयोग एक आम पाठक को अखरते हैं. कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं कोई मुद्रण की गलती तो नहीं रह गई! परंतु कुछ और प्रयोग जैसे— 'बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से, दाहिने हाथ की उंगली के नाखून तक' तथा दिनों का निम्नलिखित भाषा में वर्णन: 'गुलाबी मधुमालती वे झुमकों से झूमते, रोली अक्षत से शुभ दिन. खुली हवा से बहते दिन. यह आंके-बांके दिन. यह तीतर पाखी हल्के-फुल्के दिन. यह आकाश से आकाश तक फैले दिन" अपने आप में आकर्षक हैं, मन को छू जाते हैं, और भाषा पर लेखिका के नियंत्रण तथा उसके प्रयोग की संभावनाओं की ओर इंगित करते हैं.

लेखिका ने जहां अपर्णा के चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को सिद्धार्थ को अर्पण करने को पूरी तरह उभारा है, वहां वह सिद्धार्थ के चरित्र के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाई है. जिसके कारण सिद्धार्थ एक अवसरवादी, सच्चे प्रेम का अर्थ न समझने वाला और अपनी प्रसिद्धि का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के रूप में उभरकर आता है.

उपन्यास खत्म होने के बाद कुछ देर तक पाठक यही सोचता रहता है कि क्या कहानी समाप्त हो गई? अपर्णा का क्या हुआ? क्या वह सिद्धार्थ के छिछोरेपन को सह गई और रोजमर्रा की जिंदगी जीती रही, जैसा उसने खुद कहा था— "रोजमर्रा की जिंदगी मात्र जी लेने से— या नहीं जीने से दुःख कम या ज्यादा हो जाता है." लेखिका ने उसके चरित्र को इतना कमजोर जानकर यह सोच लिया है कि उसके पास जीवन को जिस भी रूप में वह सामने आए जीते रहने के सिवा और कोई चारा नहीं है. —अशोक बोहरा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपन्यास

जब सोचना गुनाह हो

'विचारों का इलाज' करने वाली व्यवस्था का पर्दाफाश

पागलघर
नाटक
नंद किशोर आचार्य
वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर
कीमत: 40 रुपए, पृष्ठ: 84

मानव समाज का आदिम रूप समतामूलक था या सामाजिक संरचना की बुनियाद ही विषमता पर खड़ी हुई थी, इस बहस में पड़े बिना भी साफ देखा जा सकता है कि समय के प्रवाह में जैसे-जैसे सामाजिक विधान जटिल हुआ, वैसे-वैसे सामाजिक असमानता भी बढ़ती गई. आधुनिक युग में तो इसके बड़े ही विचित्र रूप सामने आए: कहीं आजाद कराने के नाम पर गुलाम बनाने की हिकमत थी तो कहीं संरक्षण के लबादे में छिपा हुआ भितरघात. इसकी पड़ताल का मामला भी खासा पेचीदा साबित हुआ क्योंकि बहुत बार, निहित स्वार्थों के कारण, मुद्दे सुलझने की जगह और भी उलझ जाते थे.

ऐसी हालत में दलों, संगठनों, सत्ताधारियों, प्रचारकों, मताग्रहियों के प्रपंच में फंसने की जगह लेखकों-कलाकारों पर भरोसा करना शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के नाते वे समूह का हिस्सा नहीं बनते बल्कि अंतर्वृत्ति से प्रेरित स्वाधीनता और लोकहित मूलक चिंतन या सृजन करते हैं. अत्याचार जितना बढ़ता है, उसके विरोध की उतनी ही ऊंची आवाज उठाने का वे हौसला बंधाते हैं.

नंद किशोर आचार्य के ताजा प्रकाशित नाटक 'पागलघर' की विषयवस्तु यही है. पांच प्रवेशों के इस नाटक में एक लेखक के घर में पुलिस अफसर और सिपाही बिना इजाजत घुस आते हैं. उसे पकड़कर वे पागलखाने में बंद कर देते हैं क्योंकि 'पुलिस की राय' ही राष्ट्रीय राय होती है और पुलिस की राय यह है कि जो व्यक्ति टीवी नहीं देखता, जो ग्यारह बजे रात के बाद भी 'गिरजाघर में हत्या', 'अपराध और सजा' जैसी पुस्तकें पढ़ता रहता है, जो इक्कीसवीं सदी की तैयारी कराने वाले पतलून की जगह पाजामा पहनता है और जो कप या ग्लास बाएं हाथ से उठाता है, वह अस्वस्थ है और उसका इलाज पागलखाने में ही संभव है.

पागलघर के वरिष्ठ डाक्टर की जिम्मेवारी है कि वह 'विचारों का इलाज' करे क्योंकि राजनेता के कथनानुसार "व्यवहार की गड़बड़ी तो सरकार ही ठीक कर देती है." नेता चाहता है कि सब उसका साथ दें, उसकी राय ही सबकी राय हो क्योंकि "विवाद एक तरह का पागलपन है." उधर, लेखक के अनुसार: पागल वह है जो जरा सी असहमति से ही घबरा जाए और अपने डर के मारे दूसरों पर अत्याचार करने लगे. "सबसे बड़ा पागलपन है—खुद को ही राष्ट्र मान लेना और आदमी को घोड़ा समझ उस पर चढ़ने की कोशिश करना."

"विचार सबसे खतरनाक बीमारी है. छूत की बीमारी किसी एक को भी लग जाए तो फैलती ही जाती है. नहीं तो इन मानसिक अस्पतालों की जरूरत ही क्या है. बाकी पागलों को तो पुलिस का डंडा ही काफी है"
इसी किताब से

नेता की इस 'राष्ट्रसेवा' में जब लेखक जुतने को तैयार नहीं होता तो नेता के गुर्गे—वरिष्ठ डाक्टर, पुलिस और अफसर—उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं. फिर भी वह अपना 'राजद्रोह' नहीं छोड़ता और 'नेता का घोड़ा' बनने को राजी नहीं होता. सुविधाएं, सम्मान और पद उसे ललचा नहीं पाते.

इस 'लाइलाज बीमारी' का इलाज यही है कि उसे लगातार बेहोश रखा जाए. लेकिन ऐसी जिंदगी से मौत को बेहतर समझ लेखक बेहोशी की तमाम जहरीली गोलियां एक साथ निगल लेता है. नेता को पूरी छूट है कि वह इसे एक 'खुदकशी' बता दे क्योंकि "पागल अक्सर खुदकशी कर लेते हैं." लेकिन वरिष्ठ डाक्टर का सहायक—युवा डाक्टर—जो पूरे प्रसंग को अपनी आंखों से देख रहा होता है, इसे एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता और चीख उठता है कि यह तो हत्या है. इसके बाद शुरू होती है एक और लड़ाई. और वह लड़ाई है पागल हत्यारों के ढोंग का पर्दाफाश करने और आदमी को पशु-बल से झुकाकर घोड़ा बना देने के बीच....

इस नाटक को पढ़ने के क्रम में यादों के तमाम सिलसिले उभरते हैं: स्पार्टाकस, नाइंटीन एट्टीफोर, एनीमल फार्म, डॉक्टर जिवागो, फारेनहाइट 418 जिनमें नियंत्रित समाजों का चित्रण है. एक चेक फिल्म में बड़ी खूबी से दिखाया गया था कि जहां एक सहमत साम्यवादी बुद्धिजीवी सुख-सुविधामय जीवन बिताता है, वहीं एक 'असहमत' साम्यवादी को 'मनोरोगी' बता, पागलखाने में डाल, अंततः दिमाग में बिजली के झटके लगाकर वश में लाया जाता है.

बेहद प्रभावशाली थी, प्रसिद्ध निर्माता त्रूफो की फिल्म 'फारेनहाइट 418' जिसमें चित्रित व्यवस्था किताब रखने या पढ़ने को जुर्म मानती है. छिपाकर रखी गई किताबों की सूचना पाते ही आग लगाने-वाला दस्ता तुरंत उन्हें जलाने पहुंच जाता है. लेकिन उस दस्ते में भी किताबों के प्रेमी पैदा हो जाते हैं और बहुत से लोग कानून से बचने के लिए किताबें याद कर लेने का रास्ता अपनाते हैं. वे किताबमय होकर—'हैमलेट', 'वार ऐंड पीस', 'वेस्ट विंड' आदि बनकर—व्यवस्था के बदलने का इंतजार करते हैं...

विश्वयुद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान ऐसी कितनी ही कृतियां सामने आई थीं. आपातकाल के बाद और ग्लासनोस्ट, पेरेस्त्रोइका के दौरान प्रकाशित कृतियों का संदर्भ कुछ भिन्न तो होगा ही. इस दृष्टि से 'पागलघर' अवश्य पठनीय है. लेकिन उसमें कुछ स्थितियां और अनेक संवाद ऐसे हैं कि भय है—नाटकीय प्रस्तुति के दौरान कहीं त्रासद वातावरण की जगह विनोदात्मक वातावरण न बन जाए. बल्कि, पुस्तक में संकलित दूसरा विडंबनात्मक नाटक—'अरेबियन नाइट्स' की कथा पर आधारित 'जूते'—कहीं अधिक मंचोपयोगी जान पड़ता है. उसकी त्रासदी कामेडी के काफी नजदीक है.

—अजित कुमार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अंदाज़ में खूब नज़र आएं.
शर्ट और जीन्स में थिरकते जाएं.

Cambridge®

हर मूड के लिए बनी हैं ये.
हर जेब के लिए सही हैं ये.

कैजुअल शर्ट्स ● जीन्स ● ऑफिस शर्ट्स ● ईवनिंग शर्ट्स ● ट्राउज़र्स

शर्ट: रु. ७० से रु. १८०
ट्राउज़र्स: रु. १५० से रु. २९०
जीन्स: रु. १५० से रु. २५०

कैम्ब्रिज

व्यापार संबंधी पूछताछ (स्थानीय):
सुशील एंड कंपनी, १४ ए, भवानी कॉम्प्लेक्स, भवानी शंकर रोड,
दादर (पश्चिम), बंबई ४११ ०२८.

व्यापार संबंधी पूछताछ (निर्यात):
कैम एन्टरप्राइज़ेस, १५, भवानी कॉम्प्लेक्स, भवानी शंकर रोड, दादर (पश्चिम), बम्बई ४०००२८.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रसाधन सामग्री

रूमानी दुनिया की ओर उड़ान

प्रसाधनों के प्रति भारतीय महिलाओं की बढ़ती ललक

घर और बाजार के बदलते माहौल के साथ-साथ हिंदुस्तानी औरत के चेहरे-मोहरे में भी एक नया निखार आ रहा है. पांव में महावर, माथे पर सिंदूर की गोल बिंदी और कभी-कभार लिपस्टिक, नेल पॉलिश या फिर पाउडर का इस्तेमाल करके पल्लू के पीछे से मुस्कराहट के तीर छोड़ने वाली गृहिणी की ड्रेसिंग टेबल आज उसकी बदलती हुई दुनिया की एक अंतरंग तस्वीर पेश करती है.

तीन आईनों वाली ड्रेसिंग टेबल और उसमें सजी कई रंगों की नेल पॉलिश वाली शीशियां, हर सूट और साड़ी से मेल खाने वाली लिपस्टिकें, अलग-अलग रंगों और आकार वाली सेल्फ-स्टिकिंग बिंदियां, मौके और मूड के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले आई-शैडोज, पलकों को नई रंगत देने वाली मस्कारा, कांपैक्ट फेस-पाउडर, फाउंडेशन, चेहरे से चिंता की रेखाओं को ढककर चेहरे पर लाली खिला देने वाले ब्लश-ऑन और क्रीमें, नयनों की कमान को कसने वाली काजल पेंसिलें और कई तरह की जड़ी-बूटियों से बने हर्बल शैंपू... यह तामझाम जहां एक ओर फैशन के प्रति मध्यमवर्गीय गृहिणी के रुझान का परिचय देता है, वहीं अपने प्रति उसकी बढ़ती जागरूकता का आईना भी है.

बदलाव का यह क्रम पूरे भारत में कमोबेश एक जैसा है. उदाहरण के लिए मद्रास में जिस तरह परंपरागत आधी साड़ी वाली 'दावणी' का स्थान नए-नए डिजाइनों वाली सलवार-कमीज ने ले लिया है उसी तरह परंपरागत हल्दी-उबटन, काजल, शिकाकाई पाउडर और नाखून रंगने वाली मेंहदी का स्थान खूबसूरत पैकिंग वाली प्रसाधन सामग्रियों ने ले लिया है. नतीजा यह है कि भले ही वह कॉलेज की युवती हो, कामकाजी महिला हो या फिर पूरी तरह परिवार को समर्पित गृहिणी—दफ्तर, बाजार और पार्टी हर जगह वह सजी-संवरी और एक आकर्षक पहचान लिये मौजूद रहती है.

प्रसाधनों के प्रति महिलाओं की इस बढ़ती जागरूकता का ही नतीजा है कि हर शहर और कस्बे की दुकानों के शो केस नए-नए किस्म के प्रसाधनों वाली आकर्षक बोतलों, शीशियों और डिब्बों से पटे हुए दिखते हैं. पत्र-पत्रिकाओं के रंगीन पन्नों में आकर्षक व्यक्तित्व का वादा करने वाले विज्ञापनों की होड़ के साथ-साथ दुकानों पर प्रसाधनों के काउंटर भी दिन-ब-दिन बड़े होते चले जा रहे हैं. कस्बाई गृहिणियां महानगरों में रहने वाली अपनी बहनों से पीछे न छूट जा इसलिए छोटे कस्बों की परचून की दुका पर भी अब प्रसाधनों की उपस्थिति लाजि सी होती चली जा रही है.

मद्रास की एक मध्यवर्गीय बस्ती में पिछ 20 साल से दुकान चलाने वाले 47 वर्ष अब्दुल इब्राहीम बताते हैं, "पिछले पांच सा के दौरान हमारे यहां कास्मेटिक्स की बि दुगनी हो गई है. लोगों की बढ़ती जागरूक को देखते हुए मैं पत्रिकाओं और टी विज्ञापनों पर नजर रखता हूं ताकि हर चीज हमारे यहां उपलब्ध रहे."

विज्ञापनों के मामले में क्षेत्रीय पत्रिका भी राष्ट्रीय पत्रिकाओं और टीवी के सा होड़ में जुटी दिखती हैं. नतीजा यह है हर चीज पर संभल-संभलकर खर्चा क वाली गृहिणी अपने बजट में अब महीने कुछ पैसा प्रसाधनों के नाम रखने लगी है. टीवी के प्रसारण के तो यह बात अब हर प्रांत पर लगभ बराबर लागू हो रही है.

प्रसाधनों के प्रति महिलाओं बढ़ती रुचि किस तरह सर्वव्याप होती जा रही है इस बारे में बता हुए मद्रास दूरदर्शन की पार्ट-टा अनाउंसर और 29 वर्षी गृहिणी निर्मला रमण कहना है, "हमारे कॉलेज जमाने में तो लड़कियां मेक की बात भी नहीं सोच सक थीं. बहुत हुआ तो हफ्ते एक दो बार हल्दी-उबट का इस्तेमाल कर लि या फिर बालों शिकाकाई से लिया. पर अब तो भी अच्छा-खा मेकअप करने ल

प्रमोद पुष्करणा

ड्रेसिंग-टेबल सामनेः प्रसाधनों सतरंगी दुनि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

078604

अपने बारे में बताती हैं कि साड़ी बदलने के साथ उसी के मुताबिक मेकअप करना भी उनकी आदत बन गई है. यहां तक कि अब उनकी सात साल की बेटी श्वेता के लिए भी नियमित रूप से शैंपू मंगाए जाते हैं.

अपने रखरखाव के प्रति महिलाओं के बढ़ते आग्रह का एक प्रमाण उनकी ड्रेसिंग टेबल है जो बदलती प्रसाधन सामग्रियों के मुताबिक अब नए आकार और डिजाइनों में मिलने लगी हैं. दिल्ली में चंकुइयां रोड फर्नीचर मार्केट में सोबती फर्नीचर के दीपक बताते हैं, "अब तो शायद ही कोई ऐसा मध्यम-वर्गीय घर ऐसा होगा जहां ड्रेसिंग टेबल न हो. ब्यूटी पार्लर जाने का फैशन अब काफी बढ़ चुका है मगर रोजमर्रा के मेकअप के लिए तो हर गृहिणी को अपनी ड्रेसिंग टेबल का ही इस्ते-माल करना होता है." 300 रुपए से 4 हजार रुपए तक की कीमत वाली ड्रेसिंग टेबल में अब लोकप्रिय प्रसा-धन सामग्रियों की बोतलों और शीशियों के आकार के मुताबिक ही दराज और खाने बनवाए जाते हैं.

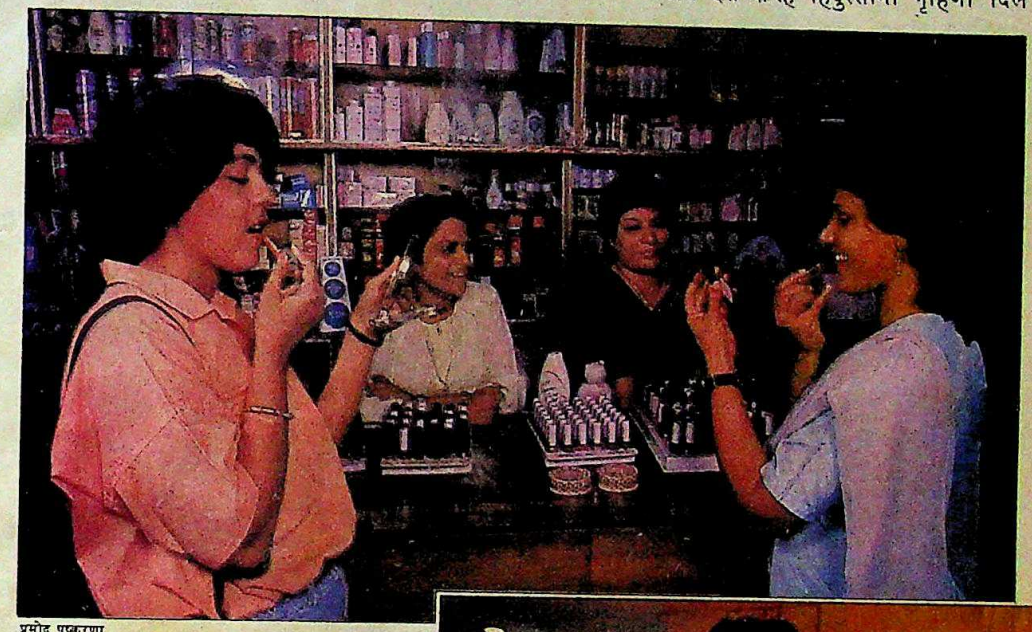

प्रमोद पुष्करणा

प्रसाधनों की मदद से अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की बढ़ती प्रवृत्ति का एक नतीजा यह हुआ है कि मद्रास हो या दिल्ली, लगभग सभी नगरों में ब्यूटीपार्लर दिखने लगे हैं. मद्रास के परंपरागत इलाके मायलापोर में अपना पार्लर चलाने वाली राम्या कहती हैं, "अगर इस इलाके में ब्यूटी पार्लर सफलता से चल सकता है तो मतलब साफ है कि मद्रासी महिलाएं भी अब किसी से पीछे नहीं हैं."

दिल्ली से सटे नोयडा इलाके में अपने ही घर में पार्लर चलाने वाली पुष्पा नाथ बताती हैं, "मेरे यहां आने वाली ग्राहकों में एक बड़ी संख्या गृहिणियों की होती है. उनमें से अधिकांश फेशियल, पेडीक्योर और मेनिक्योर कराने वाली होती हैं. बाद में वे ये सारे काम घर पर खुद ही करने लगती हैं."

दुकानों के काउंटरों पर आए दिन पहुंचने वाले नए प्रसाधनों की वजह से अब डॉक्टरों के पास पहुंचने वाले एलर्जी के मामले भी बढ़ रहे हैं. मद्रास में प्रैक्टिस करने वाले त्वचा विशेषज्ञ डॉ. ए. कृष्णा बताते हैं, "आजकल मेरे यहां आने वाले 25-30 मरीजों में से हर कम से कम छह मरीज तो प्रसाधनों से होने वाली एलर्जी वाले होते हैं. कुछ साल पहले ऐसी एलर्जी के मरीजों की संख्या महीने भर में इतनी हुआ करती थी." वे बताते हैं कि आम तौर पर यह समस्या घटिया किस्म के प्रसाधन इस्तेमाल करने से होती है. उनके मरीज प्रसाधनों के प्रति उदासीन न हो बैठें इसलिए वे अक्सर अपनी दवाएं कैलामाइन आदि में घोलकर बनाते हैं.

रसायनों पर आधारित प्रसाधनों की लोक-प्रियता के मौजूदा आलम में पारंपरिक और

(ऊपर) प्रसाधनों के काउंटर पर गृहिणियां; और ब्यूटी-पार्लर में संवरता चेहरा: बढ़ती जागरूकता

जड़ी-बूटियों वाले प्रसा-धनों को भी नया जीवन मिल रहा है. लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए अब लॅक्मे और हिमानी जैसी कंपनियां भी जड़ी-बूटियों पर आधारित प्रसाधन बाजार में ले आई हैं. इनमें काजल वाली पेंसिल, हल्दी पर आधारित वैनिशिंग क्रीम, खीर, दूध और नारियल पर आधारित रंग निखारने वाली क्रीम, बाल धोने के लिए शिकाकाई युक्त शैंपू और बाल रंगने वाली मेंहदी जैसे प्रसाधनों के विज्ञापनों पर ये कंपनियां हर साल लाखों रुपए खर्च करती हैं.

बंबई से आकर मद्रास में बसी मोनिका पाल्टा इन दिनों अपने घर से ही जड़ी-बूटियों पर आधारित प्रसाधन तैयार करके बेचती हैं.

श्याम टेकवानी

प्रसाधनों के बारे में मद्रास की गृहिणियों के बदलते नजरिये के बारे में वे बताती हैं, "पहले तो बहुत कम महिलाएं प्रसाधनों में रुचि दिखाया करती थीं. पर अब तो वे अपनी त्वचा और बालों की रौनक बनाए रखने के प्रति इतनी उत्सुक हैं कि वे इन पर दिल खोलकर पैसे खर्च करने को तैयार रहती हैं."

और इस तरह हिंदुस्तानी गृहिणी दिल और पर्स खोलकर जिस तरह प्रसाधनों की नई लहर का स्वागत कर रही है उसे देखते हुए अब यह लगभग तय है कि अपने रूपरंग और व्यक्तित्व के प्रति उसकी यह नई जागरूकता उसे उस रुमानी दुनिया में ले जाने वाली है जिसका वादा प्रसाधन सामग्रियों से जुड़ा हर विज्ञापन करता है.

—ललिता विलीप मद्रास में और विजय क्रान्ति दिल्ली में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नामम भोजानी

रॉक मशीनः जबरदस्त धूमधड़ाका

◆ हिंदुस्तानी दिल और पांव केवल विदेशी रॉक संगीत पर ही थिरकते हों, ऐसा नहीं. पिछले हफ्ते बंबई के देसी रॉक ग्रुप **रॉक मशीन** ने अपना नया संगीत एलबम 'रॉक-एन-रोल रेनेगेड' जारी किया और 'यूरोप' तथा 'नाजरथ' के कार्यक्रम से पहले ही बंबईवासियों को संगीत से सराबोर कर डाला. 6 सदस्यों वाली यह हिंदुस्तानी मंडली गत जून में भी सोवियत नागरिकों को अपने संगीत का स्वाद दे चुकी है. अपने सोवियत अनुभव के बारे में मंडली के सदस्य मार्क सेल्विन का कहना था, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगीत उपकरणों को बजाने का अनुभव ही अनूठा था.'' उम्मीद की जाए कि उनका संगीत भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिलों को जीतने वाला साबित होगा.

राजन पोडुवाल

चेरियन, शाइनीः सही ट्रैक

◆ दो साल पहले हुए एशियाड मुकाबलों में भले ही **शाइनी अब्राहम** (24) अपने ट्रैक से खिसककर गलत ट्रैक में चली गई

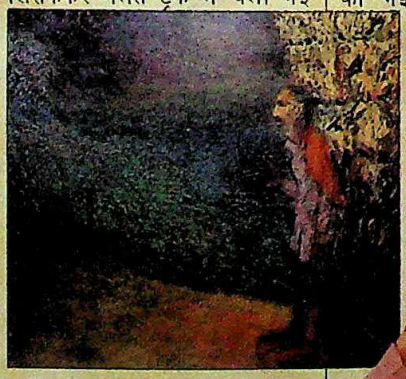

सुंदरमः कला की कीमत

डेगराः शरीर ही सोना

◆ कुदरती खजाने के मालिक हैं 32 वर्षीय **प्रेमचंद डेगरा**, जिन्हें गठीले शरीर के लिए पिछले दिनों 'मिस्टर यूनिवर्स' चुना गया. पिछले पखवाड़े ब्रिस्बेन की प्रतियोगिता से गोल्ड मैडल लेकर लौटे डेगरा का कहना था, ''मुझे उम्मीद है कि इस मैडल के बूते मुझे सरकारी मदद भी मिलेगी.'' मगर इस खिलाड़ी को शायद सरकारी मदद का मुंह नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि टिस्को कंपनी में काम करने वाले डेगरा को अब फिल्मों में अभिनय के कई प्रस्ताव मिल चुके हैं. देखें फिल्म नगरी में यह गबरू जवान क्या गुल खिलाता है.

◆ पिछले पखवाड़े 35 वर्षीय **अनूप जलोटा** भले ही अपनी शादी के कारण अधिक चर्चित रहे हों पर भजनों के इस लोकप्रिय गायक की दूसरी व्यस्तताएं भी कम नहीं थीं. लंदन में 'हरे रामा हरे कृष्णा' के भक्तों की आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम पेश किया जिसमें 30 हजार पौंड की आय हुई. एक मंदिर से जुड़े मुकदमे में उनकी आर्थिक सहायता के लिए जलोटा ने अपना हार-मोनियम भी नीलामी पर लगा दिया, जिसे एक भारतीय रेस्तरां मालिक ने 3200 पौंड में खरीद लिया. उनका कहना था, ''हरे रामा वालों से मैं कभी भी फीस नहीं लेता. उनके साथ मेरा लगाव है.''

जलोटाः फीस के बिना

चेरियन का हाथ पकड़कर
भर एक ही ट्रैक पर दौड़ने (
की कसम खाई. दोनों की
तीन साल पहले पटिया
संस्थान में हुई थी. और
हनीमून दिल्ली में होने वाले
याई ट्रैक ऐंड फील्ड मुकाब
कोचिंग कैंप में मनाएंगे.

◆ इराक से युद्ध के नगा
बाद अब कला की खुशबू आ
है. भारतीय चित्रकार
सुंदरम ने पिछले दिनों बगद
हुए अंतरराष्ट्रीय कला समा
खासी वाहवाही लूटने के
15 हजार डॉलर का पुरस्का
गोल्ड मैडल भी जीता. 57 दे
चित्रकारों की लगभग 2
पेंटिंग्स की यह नुमाइश
सद्दाम आर्ट सेंटर में आ
की गई, जिसमें अमृता
के 45 वर्षीय
सुंदरम की कृतियों
भरकर सराहा गया

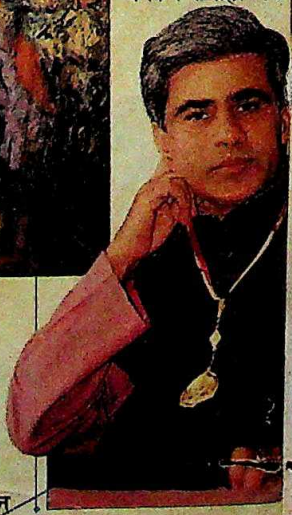

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के बिना

कड़कर
दौड़ने (
ीनों की
टिया
और
होने वाले
ड मुकाब
एंगे.

के नगा
ुशबू आ
त्रकार
दिनों बग
ला समा
टने के
पुरस्का
ता. 57 दे
भग 2
माइश
में आ
अमृता
वर्षीय
कृतियों
हा गया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Compiled
1999-2000

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar